1908

Jan-J

C. K. V.

111155

111155

1844
8/3/1.96

111155

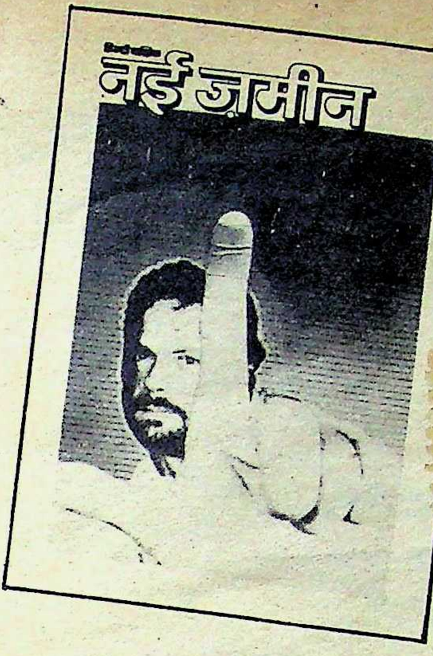

- भारतवर्ष की ९० प्रतिशत मज़लूम जनता का तर्ज़ुमान !
- धर्मनिरपेक्षता एवम् लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिये तथा शोषित जनता की आवाज़ को नई शक्ति देने वाले उर्दू साप्ताहिक "[illegible] दुनिया" का हिन्दी प्रकाशन !

कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार
111155

शोषण और नाइंसाफी के खिलाफ एक नई आवाज़...

हिन्दी पाक्षिक

नई ज़मीन

जनवरी '88 के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित हो रहा है !

२२७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२२५७, कलकत्ता
र्यालय : स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए पार्क
ट, कलकत्ता फोन : २६६०३५

surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh,
pur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari,
llong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For
gartala, it is 25 paise.

बिहार : क्या
आतंककारी हैं ?

© इस अंक में प्रका

स्थिति वाले विक्रेता बन्धु सम्पर्क करें !

BLISS

स्कॉटडेल, युएसूए निवासी श्रीमती केथलीन ब्लेकबर्न
बंदर छाप काले दंतमंजन की ही
सिफ़ारिश क्यों करती हैं?

"आपको यह बतानेके लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ कि
आपका उत्पादन बंदर छाप काला दंतमंजन इस्तेमाल करनेमें मुझे कितना आनंद मिलता है.
दंतमंजन बेशक उत्तम श्रेणीका है और इसके गुण भी लाजवाब हैं.
मैं बड़ी खुशीके साथ अपने स्नेहीयों से इस दंतमंजनकी सिफारिश करती हूँ.... "

(श्रीमती ब्लेकबर्न के पत्रसे)

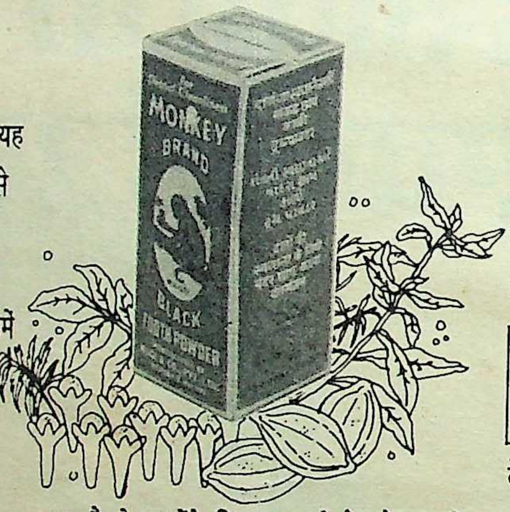

देश और विदेशमें हमारे लाखों ग्राहकों में से यह केवल एक उदाहरण है, जो हमारे उत्पादनसे संतुष्ट है. क्यों?

इसका कारण यह है कि नोगीमें, हम गुणवत्तामें अपार विश्वास रखते है और बाकी सब अपने ग्राहकोंकी, सुझ-बुझपर छोड़ देते है, जैसे श्रीमती ब्लेकबर्न तथा अन्य...

और बंदर छाप काले दंतमंजन की इस कामयाबी का राज़ छुपा है इसके **आयुर्वेदिक फार्मुलेमें. मेन्थॉल, थाइमॉल,** (विशेष रूप से फ्रान्स से आयात किया हुआ), **लौंग तेल** तथा अन्य जड़ी-बूटियों की नपी-तुली मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है. इसे विशिष्ट कालावधि तक परिपक्व होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे परिपूर्ण सुगंध पैदा होती है. इस दंतमंजन में शामिल हर एक तत्त्व की दंतचिकित्सा में अपनी विशेष महत्ता है. थाइमॉल एक जन्तुनाशक तत्त्व है जो मसूड़ोंके लिए गुणकारी है. लौंग का तेल दांतों के दर्द से राहत दिलानेके लिए सुप्रसिध्द है और मेन्थॉल ठंडे स्वादवाला एक कोमल दर्दनिवारक है.

यही नहीं, इसमें हरडा के अतिरिक्त गुण भी शामिल है जो मसूड़ोंको जकड़नेमें मदद करती है और छालोंसे आराम पहुँचाती है. अंतमें, सबसे महत्त्वपूर्ण है इसका कोयला का आधार, जो बंदर छाप काले दंतमंजन को लोकप्रिय बनाता है - दांतोंको चमकदार और सफेद बनानेमें वचनबद्ध है.

इसका कारण यह है कि कोयला दुर्गंधका नाश करता है और दातों को सफ़ेद बनाता है. इसीलिए बंदर छाप काला दंतमंजन आपके दांतोंको ज्यादा साफ और ज्यादा सफ़ेद रखता है.

तो फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि ७५ वर्षोंसे बंदर छाप काला दंतमंजन न केवल भारतमें बल्कि दुनियाभरमें प्रेमपूर्वक अपनाया गया है. क्योंकि श्रीमती ब्लेकबर्न की तरह अधिकतर लोग अपने दातोंकी सही देखभाल के लिए किसी और दंतमंजनपर भरोसा नहीं करते.

बंदर छाप
काला दंतमंजन
७५ वर्षों से
दुनियाभरमें विश्वसनीय

नोगी

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक १

१५ जनवरी, १९८८

माया

9-c

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

यह अंक

आवरण कथा

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मंदिर के विवाद ने पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रखा है। लेकिन क्या इतिहास में ऐसे साक्ष्य हैं कि राम जन्मभूमि तोड़कर बाबर ने अपने नाम पर मस्जिद बनवायी थी? भावोन्माद से हटकर तर्क के आधार पर इस सवाल पर विचार हो सके, इसके लिए 'माया' नये ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। ३०

फेयरफैक्स जांच आयोग

फेयरफैक्स जांच आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि वी०पी० सिंह षड्यंत्री साबित हो रहे हैं? ८६

राजस्थान

इंका सरकार और इंका संगठन् में आपस में ठनी हुई है। इस 'युद्ध' के कारण कौन- कौन से नजारे सामने आ रहे हैं? ६०

१९८७ वर्ष

विदा ले रहे १९८७ की वे कौन सी घटनाएं हैं जो खास अहमियत रखती हैं? १९८७ की घटनात्मक डायरी: १६

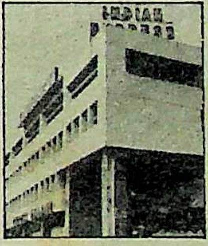

ग्वालियर में शादी

ग्वालियर राजघराने में जैसी वैभवपूर्ण शादी हुई है, क्या वह अकाल मे जूझते देश और लोकतांत्रिक परंपरा का मजाक नहीं? १३

सड़क दुर्घटनाएं

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं दिनोदिन बढ़ रही हैं। क्या इन दुर्घटनाओं को बढ़ाने में 'मारुति' जिम्मेदार हैं? ६९

भोजपुरी फिल्में

भोजपुरी बोलने वालों की संख्या काफी होते हुए भी भोजपुरी फिल्में उपेक्षित क्यों हैं? रजत जयंती के संदर्भ में भोजपुरी फिल्मों का मूल्यांकन: ९९

दिल्ली दरबार: जब देखा जो आइना उन्होंने... ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
अभिमत: राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव करायेंगे: भवानी सेन गुप्त २४
अर्थतंत्र: नये साल को विरासत में क्या मिलेगा? २६
बेढब २८
म०प्र०: बाप तो बाप, लेकिन बेटी भी! ५०
बिहार: क्या प्रभुनाथ सिंह आतंककारी हैं? ५३
बिहार: कुएं के लिए पूर्व विधायक की हत्या ५४
बिहार: दुबे के हजार दिन ५५
उ०प्र०: सरकार क्यों नहीं कराती नगरमहापालिकाओं के चुनाव? ६४
खेल: दक्षिण एशियायी खेल: भारत का वर्चस्व बना रहा ७५
व्यक्तित्व: ब०व० कारंत से विशेष साक्षात्कार ७८
विदेश ८४
परदे के पीछे ९४
कार्टून ९७

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया
भारतीय
पार्टी
का
चन्द्रास्वामीः
क्या डबल एजेंट हैं!

देशद्रोही हैं स्वामी नहीं

आपने ३१ दिसंबर; ८७ की 'माया' के 'क्या चंद्रास्वामी डबल एजेंट हैं ?' लेख में विस्तृत जानकारी दी। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रास्वामी एक देशद्रोही हैं। नाम के बाद तो स्वामी लगाते हैं, लेकिन वह अपने देश के प्रति द्रोह का कार्य ही करते हैं, इसलिए उन्हें स्वामी नहीं कहा जा सकता। शायद भारत सरकार अंधी है जो इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती। **—सोहन लाल शुक्ल, ग्राम-लखनीपुर फरेन्दा, पोस्ट-बलरामपुर,**
गोण्डा, उ०प्र०

वोरा हटाओ मुहीम

'माया' के दिसंबर अंक (संयुक्तांक) में 'वोरा-हटाओ' मुहीम पढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को हटाने की मुहीम वास्तविक रूप से तभी शुरू हो गयी थी जब वोराजी के मुख्यमंत्रीत्व काल के दो ही माह हुए थे। अर्जुन सिंह व उनका गुट तभी से सक्रिय हो गया, क्योंकि वह अपने समधीज़ी अर्थात दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे ताकि प्रदेश में शाही राज बना रहे।

जब तक मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को प्रधानमंत्री का सहयोग प्राप्त है तब तक कोई भी गुट वोराजी को अपदस्थ नहीं कर सकता।**—गुरुदेव सिंह भाटिया, ५-गणेश गंज सेंधवा, प० निमाड़, म०प्र०**

पटनायक का करिश्मा

'माया' के दिसंबर अंक में 'पटनायक का करिश्मा' पढ़ा। पटनायकजी [illegible] क्षेत्रों में जूझ रहे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे निश्चय ही एक दिन मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को खतरा पैदा हो सकता है। पटनायक महोदय ने जिस तरह राजीवजी को चकमा दिया है, वह अपने आप में एक कहानी है। राजीवजी को चाहिए कि वह एक निष्पक्ष व ईमानदार पर्यवेक्षक को भेजकर उस राज्य के राजनीतिक संकट और जनता के संकट का सही आकलन करवायें।**—राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अण्डाल, बर्दमान, प० बंगाल**

देशी अफसरों को विलायती प्रशिक्षण

'माया' के नवबर द्वितीय अंक में प्रकाशित 'देशी अफसरों को विलायती प्रशिक्षण' पढ़ा। इसी से पता चला कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को अमरीका व ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना को गृह राज्यमंत्री पी० चिदंबरम ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। विजय कुमार यादव, सांसद ने इसका विरोध कर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। यह देशी अफसर विदेशों में जाकर वहां की चकाचौंध व विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। पी० चिदंबरम जी को यह नहीं मालूम है या वह भूल गये हैं कि भारतवर्ष की ८० प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जिसमें अधिकांश निरक्षर व अपढ़ होते हैं और इन्हीं में से बने यह देशी अफसर विलायतों में प्रशिक्षण पाकर देशी जनता पर विलायती परंपरा का शासन करेंगे। वे भारतीय जनता पर अंग्रेजों जैसा कठोर शासन कर उनकी मूल भावनाओं को कुचल देंगे। यदि इन अफसरों को प्रशिक्षण देना ही है, तो भारत के सुदूरवर्ती गांवों में दिया जाये। उन्हें विकास-क्षेत्रों में 'विकास प्रमुख' के रूप में नियुक्त किया जाये, तभी ये सही मायने में भारतीय जनता की भावना को परख पायेंगे। एक ओर भारत भयंकर सूखे से गुजर रहा है, तो दूसरी ओर बाढ़ की विभीषिका से तबाह हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देना, कहां की बुद्धिमानी है ? इन अफसरों को विदेशों के बजाय गांवों में प्रशिक्षण देना राष्ट्र के हित में अति उत्तम होगा और भारत जासूसी से भी मुक्त रहेगा।**—छंगा प्रसाद, ए २१२, आवास विकास कालोनी, सीतापुर**

'क्या चद्रास्वामी डबल एजेंट हैं ?' लेख पढ़ा। इन ढोंगी साधु-संतों ने हमेशा देश का बुरा किया है। पहले तो यह सत्ताधारी दलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, मगर जब दाल नही गलती, तो येन-केन प्रकारेण सत्ता को उलटने में लग जाते हैं। अपने इस कार्य में वह देशी-विदेशी किसी भी तरह की सहायता लेने से बाज नहीं आते। रही विदेशियों की बात, तो वह कथित अध्यात्म के झांसे में आकर चमत्कारों पर यकीन कर लेते हैं और इन्हें अपना गुरु बना बैठते हैं। खशोगी, एलिजाबेथ, थैचर आदि इन्हीं अंधविश्वासों से पीड़ित हैं। **विजय सिंह, कोतमा रोड, बुढ़ार जिला-शहडोल (म०प्र०)**

मध्यावधि चुनाव

'माया' के नवंबर द्वितीय पक्ष, १९८७ में मध्यावधि चुनाव की आशंका के बारे में पढ़कर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मध्यावधि चुनाव की कोई गुंजाइश तो नहीं दिखती, न ही जरूरी है। यह सिर्फ अफवाह मात्र है जो विपक्ष द्वारा फैलायी गयी है तथा कुछ अखबार व पत्रिका इनका साथ दे रहे हैं। वैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। जनता के सामने सही तथ्य आने चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा है। **—देवी सिंह सांखला, सांखला हाउस (पुलिस थाने के पीछे), लूणकरणसर, बीकानेर**

'माया' का ३० नवंबर का अंक पढ़ा। राजनीतिक पर्यवेक्षक भवानी सेन गुप्त की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि इंदिरा कांग्रेस गुप्त रूप से मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। कुछ कांग्रेसी नेताओं का तर्क है कि कोई विपक्षी पार्टी इतनी प्रबल नहीं जो कांग्रेस-इ का विकल्प बने, लेकिन वी०पी० सिंह का बढ़ता जनाधार, विपक्षी एकता की संभावनाएं, व्यापक भ्रष्टाचार, प्रेस आजादी पर कुठाराघात, बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी से त्रस्त भारतीय जन-मानस खुली हवा में सांस लेने को बेचैन है। लेकिन वर्तमान भारतीय अर्थ व्यवस्था इतनी लुंज-पुंज है कि मध्यावधि चुनाव में इसकी रीढ़ ही टूट जायेगी। **—त्रिभुंवन प्रसाद सिंह, मैनेजर ट्रिपुल सी०, छतहार, भागलपुर**

आवरण कथा 'क्या मध्यावधि चुनाव होगा ?' में अच्छा तो होता कि इस विषय पर आप अपने पाठकों से प्रश्न चर्चा या परिचर्चा के अंतर्गत विचार आमंत्रित करते। भले इसे राजनीति में दखलंदाजी माना जाये, किंतु यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। जन-तत्र में तो उलझन और विवादास्पद मसलों पर जनता की राय लेना सही समझा जाता है और यदि इतने उथल-पुथल के बाद भी जन-प्रतिनिधि (वह भी सुलझे विचारोंवाला नयी पीढ़ी का व्यक्ति) अपनी विश्वसनीयता पर अपने संदेह का निवारण जनता से करवाना न चाहे, तो पत्र-पत्रिकाओं को तो यह दायित्व निभाना चाहिए, किंतु उस तरह नहीं, जिस तरह नवंबर (द्वितीय पक्ष), १९८७ के अंक में 'माया' ने निभाया है। **—जितेन्द्र पाल सिंह, मारफत श्री सुधीर कुमार मिश्रा, भूमि विकास बैंक आरा, भोजपुर, बिहार**

'माया' (द्वितीय पक्ष) हाथ में आते ही इसके पन्नों को पलटने लगा। जब पृष्ठ ३० आंखों के आगे आया तो पहले इसे पूर्णरूपेण पढ़ डाला। अभी हमारा देश बाढ़, सूखा, पंजाब-समस्या और श्रीलंका में शांति सेना का खर्चा उठाकर पहले से ही परेशान है और ऐसे में मध्यावधि चुनाव कराने से देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। अभी जबकि चुनाव की अवधि पूरी होने में दो वर्ष और बाकी हैं, तो यह घबड़ाहट कैसी ? चुनाव यदि अपने वक्त पर हो, तो अतिरिक्त खर्च से हम बच जायेंगे और तब तक हम उपर्युक्त मामलों से छुटकारा भी पा लेंगे। 'ऐसी कठिन परिस्थिति में सत्ता-पक्ष और विपक्ष मिलकर कार्य करते, तो देश का और भला होता। **—सुनील पाण्डेय, राजा बाजार, मोतिहारी, पूर्व चंपारण, बिहार**

आवरण कथा 'क्या मध्यावधि चुनाव होगा ?' पढ़कर अनेक शंकाओं का निवारण हुआ। अगर राजीव गांधी चुनाव कराते हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि राजीव कमजोर पड़ चुके हैं। जिस प्रकार का बहुमत इन्हें १९८४ के चुनाव में मिला था, उसे पाकर राजीव गांधी ने सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता में अनाप-शनाप निर्णय लिये। बिना सोचे-समझे समझौता नीति अपनायी जिसके गलत परिणाम निकले।

इलाहाबाद में आगामी दो-तीन महीनों में उप चुनाव होना है। आप लोगों को बतायें कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद के लिए क्या किया ? सभी हवाई तीर छोड़ते रहे। नारायण दत्त तिवारी ने काशीपुर को उत्तर प्रदेश का जापान बना दिया। वीर बहादुर सिंह ने गोरखपुर में कई योजनाएं शुरू करवायीं, अमेठी के बारे

में क्या कहें? आज लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह को कह सकते हैं कि वह उ०प्र० के मुख्यमंत्री रहे, फूलन देवी से मोर्चा लिये, लेकिन इलाहाबाद के लिए क्या किया? अमिताभ बच्चन जब लोकप्रियता की चरम सीमा पर थे, तब उनको याद भी नहीं रहा कि यहां इनका जन्म हुआ था। चुनाव लड़ना हुआ, तो इलाहाबादी बन गये। क्या कहें, इन नेताओं को, सभी अपना मतलब निकालते हैं। अब उप चुनाव में जो भी खड़ा होगा, वह कहेंगा कि हमसे बड़ा इलाहाबाद का संरक्षक और कोई है ही नहीं? **—अजय कुमार सिंह, ५२७/३०, नेहरू नगर, मीरापुर, इलाहाबाद**

किसानों को बोतल में बंद जिन समझते हैं

शरद जोशी का साक्षात्कार 'किसानों को बोतल में बंद जिन समझते हैं' पढ़ा। शरदजी की इंडिया और भारत की नूतन अवधारणा देश की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर देती है। आज से ४० वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्ति दरअसल इंडिया ने पायी थी। भारत के बारे में तो सचाई यह है कि ब्रिटिश शासन की गुलामी से छुटकारे के साथ ही तथाकथित स्वदेशी शासन का जुआ उसकी गर्दन पर धर दिया गया।

मात्र सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथों से काले अंग्रेजों के हाथों में आ गयी। भारत को आजादी मिलनी बाकी है और यह मिलकर रहेगी। यदि शरद जोशी व महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग 'एक लीटर दूध के लिए गाय पालना कोई अक्लमंदी नहीं' वाली बात पर टिके रहकर राजनीति से दूर रहें तो। **—सुरेंद्र सिंह दांगी, ग्रा०पो० कुल्हार, गंज बासौदा, म०प्र०**

अफसरों को कलंकित न करें

'**प्र**शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम के अंतर्गत अफसरों को विदेश में भेजना चाहिए ताकि वे शिक्षण पद्धति, प्रकरण-लेखन, पाठ्यक्रम-निर्धारण विज्ञान के संबंध में नयी जानकारियां प्राप्त कर अच्छी कुशलता अर्जित कर सकें जबकि हमारे यहां पर ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। पर हमारे देश के रामधन और मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे नेता बेबुनियादी तौर पर गलत रूप से अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अफसर विदेशी एजेंट बन जायेंगे। क्या देश-भक्ति का ठेका इन्होंने ही ले लिया है? जबकि विदेश भेजे जाने वाले सभी अधिकारी अपने देश से विश्वासघात नहीं करते हैं। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण-व्यवस्था विकसित करनी होगी। **—ईश्वरी प्रसाद शर्मा, मदनगंज-किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान**

स्वागतयोग्य किंतु आपत्तिजनक

'**मा**या' नवंबर द्वितीय अंक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की महापरियोजना संबंधी लेख पढ़ा। उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। चंद्रमोहन (२७२ खुड़बुड़ा) के मकान को तोड़े जाने की घटना दिनांक १६.१.८७ की है। आपने ७ फरवरी, ८७ लिखा है जोकि गलत है। आपने मेरी फोटो के नीचे लिखा है कि विकास शुल्क न देने पर मकान टूटा। इस पर प्रार्थी को घोर आपत्ति है। शायद यह वाक्य मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के पदेन अधिकारियों ने अपनी धूमिल छवि को साफ करनें हेतु लिखाया है। **—चंद्रमोहन, २७२ खुड़बुड़ा, देहरादून**

जगद्गुरु निरंजन देवतीर्थ

पुरी के शंकराचार्य जगद्गुरु निरंजन देवतीर्थजी महाराज के साक्षात्कार से मालूम पड़ता है कि वह हिंदू शब्द का अर्थ भी नहीं जानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के विषय में जो भी ज्ञान रखते हैं, वे भ्रामक हैं। इसलिए सती दाह के संबंध में उनके मत भी असत्य हैं। मैं हिंदू शब्द पर शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। इसका अर्थ भू-पुत्र होता है। जो भी जीव या वस्तु पंचभूत से बना हो या आधार मानता हो, वह हिंदू है। जो भी दुर्गतिनाशिनी दुर्गा माता के चार अंशों ज्ञान (गणेश), विद्या (सरस्वती) समृद्धि (लक्ष्मी) और शक्ति (कार्तिक) पर विकास के लिए आश्रित हो, वह हिंदू है। हिंदू छोड़ कर इस धरती में कोई जाति नहीं है। इतने सारे धर्म और जाति की मान्यता धर्मगुरुओं की करामात है। **—तारक नाथ मुंडा, ग्राम विजार, पो० दलभंगा, सिंहभूम, बिहार**

कमलापति त्रिपाठी

जगन्नाथ मिश्र

जीतेंद्र

आज कांग्रेस का विकल्प वही कांग्रेस हो सकती है जो गांधीजी द्वारा स्थापित किये गये नैतिक आधारों पर रहकर जवाहरलालजी द्वारा दिखाये गये वामपंथी झुकाव को बनाये रख सके।**—'दिनमान' के अतिथि संपादक कमलापति त्रिपाठी, 'दिनमान' में**

राजीव गांधी को तो छह बार इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के बाद तो उनकी पार्टी ने सात में से छह चुनाव हारे हैं।**—पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से यह पूछे जाने पर कि गुंटूर चुनाव में हार जाने के बाद क्या एन०टी०आर० को इस्तीफा दे देना चाहिए? 'टेलीग्राफ' में**

भारत का तख्त और ताज इन दिनों बंबई के कुछ पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद होकर रह गया है।**—वी०पी० सिंह, 'जनसत्ता' में**

कांग्रेस-इ के नेता राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जैसे विवादों के समाधान में रुचि नहीं रखते, इसके बजाय वे 'हिंदू राष्ट्रवाद' की लहर पर १९९० का चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं।**—सैयद शहाबुद्दीन, 'दैनिक जागरण' में**

फेयरफैक्स ने जांच का नहीं, केवल पोस्ट आफिस का काम किया है।**—ठक्कर नटराज आयोग की रिपोर्ट से**

दुबे (बिंदेश्वरी) के नेतृत्ववाली बिहार सरकार केवल जमींदारों और औद्योगिक माफिया की हितरक्षक भर रह गयी है।**—बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र, 'पैट्रियाट' में**

राजीव गांधी भारत के, अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं।**—लोकदल-अ महासचिव सुब्रह्मण्यम स्वामी, 'स्टेट्समैन' में**

इस मोरचे (जनमोर्चा) में शामिल होने से हमें घाटा ही रहेगा और जिस तरह हमारी उपेक्षा की गयी है, उससे अब इसमें शामिल होने में सम्मान भी नहीं है।**—हेमवती नंदन बहुगुणा, 'चौथी दुनिया' में**

मैं कभी व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता।**—अरुण नेहरू, 'रविवार' में**

मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि दूतों और केंद्र सरकार के संपर्कों के बहकावे में आ जाऊं।**—प्रकाश सिंह बादल, जेल से रिहाई के बाद, 'नभाटा' में**

आज कांग्रेस संस्कृति ही ऐसी बन गयी है, जो गाली दे या दंगा कराये, उसे दिल्ली दरबार से पुरस्कार स्वरूप कोई-न-कोई पद मिल जाता है।**—जनमोर्चा के जफर अली नकवी, 'अभयभारती' में**

अगर मैं कल मर जाऊं, तो निश्चिंत होकर मरूंगा कि देश सुरक्षित हाथों में है।**—राजीव के प्रधानमंत्री बनने के समय गोयनका के विचार 'धर्मयुग' में**

कांग्रेस के नहीं, राजीव गांधी के विकल्प की बात कीजिए।**—मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत**

मैं फिल्मों में इसलिए आया कि पढ़ने में [illegible] नहीं लगता था।**—जीतेन्द्र, 'माधुरी' [illegible]**

जब देखा जो आइना उन्होंने...

नये साल—१९८८ का सूरज जब नयी रोशनी लेकर दिल्ली दरबार पहुंचा, तो उसे तुरंत लौटा दिया गया, "बाबा कोई और घर देखो। यहां सूखा पड़ा हुआ है। देने को कुछ नहीं है। अभी-अभी दिल्ली दरबार लक्षद्वीप में साले-सालियों के साथ क्रिसमसी धमाचौकड़ी मचाकर थकान से चकनाचूर हैं, क्यों उन्हें जगाकर 'बोर' करने पर आमादा हो। चलो-चलो, आगे बढ़ो...।" नये साल का सूरज मुस्करा कर लौट लिया। लेकिन चोर चोरी से जाता है, हेराफ़ेरी से नहीं। जाते-जाते उसकी कुछ किरणें दिल्ली दरबार को छेड़ ही गयीं। सूरज की किरणों का छेड़ना था कि पूरे दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। दरबारी भयाक्रांत होकर उसी तरह भागने लगे, जैसे जहाज में आग लग जाने पर चूहे भागते हैं। दिल्ली दरबार भौंचक्का होकर अपने डनलपी डबल बैड पर रोशनी के आ जाने से 'हाईजम्प' लगायें कि उसके पहले ही मध्यप्रदेशी मोतीलाल वोरा का बोरा उतारकर उनके ऊपर डाल दिया गया। गहरी नींद में डूबे दिल्ली दरबार चौंके जरूर, लेकिन दरबारियों ने 'मैनेज' कर लिया।

पिछले दिनों सूखा-राहत कार्यों का आइना दिल्ली दरबार ने मुख्यमंत्रियों को दिखाया था। रामकृष्ण हेगड़े के सामने जैसे ही आइना आया, वह कर्नाटकी राग अलापने लगे। एन०टी० रामाराव ने पीत वस्त्र धारण करके विवेकानंद का 'पोज' ले लिया। देवीलाल ने आइने के सामने अपने को पीछे करके, अपना पूरा कुनबा सामने कर दिया, "देखो कितनों को मैंने राहत पहुंचायी है।" जानकी पटनायक ने आइने के सामने अपनी 'जानकी' को पहले आगे करने की कोशिश की। जब उनकी जानकी (जयन्ती पटनायक) यह कह कर सामने से हट गयीं कि मैं एम०पी० हूं। मेरा भी दांव मिनिस्टरी में लग सकता है, तो जानकी पटनायक कालाहांडी अपने हाथ में लेकर 'पटनायक' की जगह 'खलनायक' के रूप में खुलकर सामने आ गये, "तुम्हें जो बिगाड़ना है, बिगाड़ लो। मैं भी देख लूंगा।" राजस्थानी हरिदेव जोशी जब रूपकुंवर की 'सती माला' गले में डाले हुए आइने के सामने आये, तो उनका दूसरा हाथ भी गायब था। दिल्ली दरबार का कलेजा मुंह को 'दया भाव' से आ गया, "घबरा मत सती-भक्त हरिदेव। मैं अपना पूरा काबीना लेकर तेरे जंगलों में पिकनिक मनाने आ रहा हूं।" गुजरात के अमर सिंह चौधरी के सामने जैसे ही आइना आया, तो उन्होंने चेहरे की जगह पीठ उसके सामने कर ली। जब उनको बार-बार आदेश हुआ कि आइने के सामने चेहरा करो, तो वह बोल उठे, "जितने कोड़े [illegible]ना हो लगा लो, लेकिन चेहरा दिखाने के लिए नहीं।" उत्तरप्रदेशी वीर बहादुर सिंह की बारी [illegible]री में आने वाली थी। लेकिन वह आइने में काफी पहले से ही ताक-झांक किये जा रहे थे। जबसे उन्होंने सोनिया गांधी को इलाहाबाद के लोकसभा उप चुनाव में भिड़ा देने की शतरंजी चाल चली वह समझने लगे हैं कि उनके चेहरे पर 'नूर' बरसने लगा है। वह पंक्ति तोड़कर आइने के सामने आ गये। जब उनको आइने में कोई बदरंगी चेहरा दिखा, तो पीछे घूमकर देखना चाहा कि उनके पीछे कौन-सा 'बदरंगी आदमी' खड़ा हुआ है। लेकिन पीछे दूर-दूर तक वही-वह थे। तभी उनसे सवाल पूछा गया कि आपने सूखा राहत का तीन-चार सौ करोड़ कहां खर्च किया? वीर बहादुर बगलें झांकने लगे। वीर बहादुर ने जवाब देना चाहा कि 'अभी इलाहाबाद में सोनियाजी को चुनाव लड़ना है। उसी चुनावी राहत-कार्यों के लिए वह सुरक्षित है। वहां पाई-पाई खर्च कर दी जायेगी।' वीर बहादुर हड़बड़ाये आइने के सामने खड़े हुए थे कि पीछे से उनको धकियाकर मध्यप्रदेशी वोरा को आइने के सामने खड़ा कर दिया गया। समय की कमी कहिए या फिर आइने की करामात, वोराजी का चेहरा हलका-सा आइने में आया, जो ज्यादा विकृत नहीं था। दरबारियों ने वोराजी को खींचकर एक तरफ कर लिया, "इस बोरे का सबसे कम विकृत चेहरा है। थोड़ा-सा मेकअप करने के बाद यह चल जायेगा।" उसी दिन से मोतीलाल वोरा भोपाल में कम, दिल्ली दरबार में ज्यादा दिखायी पड़ने लगे हैं। लेकिन गाहे-बगाहे जब वोराजी को कहीं आइना दिखलायी पड़ जाता है, तो वह फौरन अपना चेहरा अपने बोरे से ढंक लेते हैं। वैसे अर्जुन सिंह बराबर यह मांग कर रहे हैं कि मोतीलाल वोरा को फिर से आइने-मुआइने के लिए लाया जाना चाहिए। लेकिन उनकी भी मुश्किल यह है कि जब भी वह इस तरह की मांग पंचम में करते हैं, तो उनको आइना दिखा दिया जाता है, जिसमें उनके कंधे पर चुरहट लाटरी लदी हुई दिखायी पड़ती है। उनका स्वर धीमा पड़ जाता है। वह टेलीफोन के मंत्रालय पर चढ़े बैठे हैं, लेकिन उनका टेलीफोन दिल्ली दरबार में घंटी नहीं बजा पा रहा है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मोतीलाल वोरा के टेलीफोन की घंटी दिल्ली दरबार में टनाटन बज रही है।

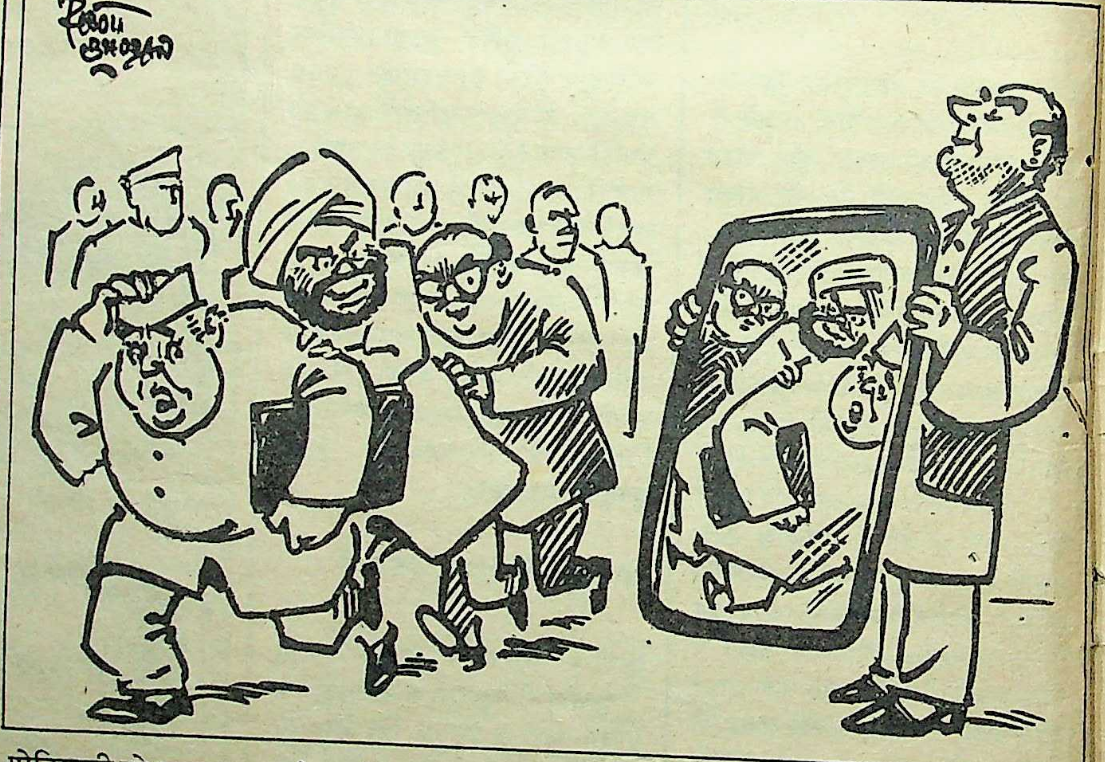

दिल्ली के ७, जनपथ में बेत की आराम कुरसी पर ऊंघ रहे बाबू (पं० कमलापति त्रिपाठी) को जब लखनऊ से आ गिरे लल्लू (लोकपति त्रिपाठी) ने झकझोरा, तो वह विशुद्ध बनारसी में भड़क उठे, "अब क्या हो गया! वीर बहादुर ने कुछ और कर दिया?" लल्लू ने बाबू के कान में मुंह 'फिट' कर दिया, "दिल्ली दरबार ने वीर बहादुर को आइना दिखा दिया है। तुम यहां बैठे-बैठे बस ऊंधियाया करते हो।" बाबू ने केदार से अपनी छड़ी लाने के लिए कहा, तो टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। लल्लू टेलीफोन के चोंगे पर लपके कि उसके पहले बहूजी (चन्द्रा त्रिपाठी) ने उसे लपक लिया, "मैं बहूजी बोल रही हूं।" दूसरी ओर से आवाज आयी, "मैं भी बहूजी बोल रही हूं। बाबू-से-बाबू बात करना चाहते हैं।" बहूजी ने टेलीफोन का चोंगा बाबू को देते हुए कहा, "शीला दीक्षित का फोन है। उमाशंकर दीक्षित बात करेंगे।" बाबू ने टेलीफोन का चोंगा अपने कान में फिट करने से पहले फबती कस दी, "इन सिंधी और सिखनी पंडिताइनों में कभी नहीं पटती है। जब हम सरजूपारी और कान्यकुब्जी बूढ़ों ने ब्राह्मणत्व को मिल बैठकर खाने के लिए समझौता कर लिया है, तो तुम लोग भी विरोधी दलों की तरह कोई काम चलाऊ ताल-मेल

क्यों नहीं कर लेती हो।" बहूजी मुंह बिचका कर एक ओर हो लीं, तो बाबू ने दूसरे से बतियाना शुरू कर दिया, "ठाकुर चाहे वह अर्जुन सिंह या वीर बहादुर या के०एन० सिंह हों, अंत में सब राजा मांडा की ही तरफ जायेंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता है। दिल्ली दरबार को अब हम लोगों का ब्राह्मणत्व ही बचा सकता है। फिर से ब्रह्म (ब्राह्मण-हरिजन-मुसलमान) को पुख्ता करना पड़ेगा।" दूसरी ओर से उमाशंकर दीक्षित ने कमलापति त्रिपाठी से कहा, "अब टेलीफोन पर ज्यादा मत बतियाओ। अभी इसके ऊपर अर्जुन सिंह ही बैठा हुआ है। तुम देरी न करो और ग्वालियर जाने से दिल्ली दरबार को रोको।" कमलापतिजी ने टेलीफोन का चोंगा रिसीवर पर ऐसे दे मारा, जैसे वह अर्जुन सिंह का सिर हो। वह उठे और लल्लू को लेकर दिल्ली दरबार में पहुंच गये।

दिल्ली दरबार को सैम पेटरोडा और कैप्टन सतीश शर्मा कंप्यूटर पर यह समझा रहे थे कि राजा मांडा के पीछे जब हमारा 'फेयरफैक्स' दौड़ेगा, तो वह बचने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ भागेगा। वहां ज्योति बसु उसे लाल किताब पकड़ाने की कोशिश करेगा। राजा मांडा लाल किताब से डरता है, इसलिए वह बंगाल की खाड़ी में कूद पड़ेगा। वह तैरता-तैरता अरब सागर में पहुंचकर केरल में घुसेगा। वहां ई० एस० नम्बूदिरीपाद उसकी गर्दन पकड़कर यह कबूलवायेगा कि वह सी०आई०ए० का आदमी है। वह अपनी जान बचाने के लिए झूठमूठ कह देगा, "हां, हां मैं सी०आई०ए० का आदमी हू। बस हम लोगो का काम चल जायेगा। हम लोग अजित पांजा को कह कर तुरन्त दिन रात टी०वी० और रेडियो पर चिल्लायेंगे कि राजा मांडा सी०आई०ए० का ही आदमी है। उसने कबूल कर लिया है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद अपने २४, अकबर रोड से उसके खिलाफ पूरा अभियान चलायेगा कि राजा मांडा सी०आई०ए० का आदमी है। राजा मांडा पूरी तरह 'फिनिश' हो जायेगा।" कमलापति त्रिपाठी ने बीच में ही बनारसी दांव मार दिया, "कतई नहीं। राजा मांडा बंगाल की खाड़ी में नहीं जायेगा। वह ग्वालियर जायेगा।"

दिल्ली दरबार ने घूमकर कमलापतिजी की तरफ देखा और आश्चर्य से पूछा, "ग्वालियर तो हम जा रहे हैं, ताकि राजा मांडा वहां न जा सकें। मुझको तो माधव राव सिंधिया ने यही कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के बहाने देश के सारे ठाकुर-रजवाड़ों को बुला रहा हूं। वहां आपकी दोस्ती उन राजा-महाराजाओं से करा दूंगा, ताकि वे लोग राजा मांडा से पूरी तरह कट जायें। उसके बाद आप मेरे समधी कर्ण सिंह को अपने दरबार में शामिल कर लेना, तो सारे हिन्दू आपके साथ आ जायेंगे।' कमलापतिजी ने बीच में ही बात काट दी, "हिन्दू! ये ठाकुर-रजवाड़े कब से हिन्दू हो गये?" पी०वी० नरसिम्हाराव की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने आगे कहा, "पी०वी० तुम तो विद्वान ब्राह्मण हो। इन लोगों को बताओ कि जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है, वह मात्र ब्राह्मण धर्म है। यह तो हम लोगों की उदारता है कि इसमें हम लोगों ने ब्राह्मण के अलावा और लोगों को ब्राह्मणों की चाकरी के लिए भरती कर लिया।" पी०वीं० नरसिम्हाराव ने लम्बी गर्दन पक्ष में हिलायी, तो दिल्ली दरबार आलथी-पालथी मारकर कमलापतिजी की तरफ एकाग्रचित हो गये। कमलापतिजी ने गद्गद होकर बाबा विश्वनाथ को मन-ही-मन याद किया और 'काशी के पंडे' के असली रूप में आ गये, "निकालना ही पड़ेगा। वीर बहादुर सिंह, अर्जुन सिंह, के०एन० सिंह को ही नहीं, बल्कि जिसके नाम के आगे सिंह लगा हो, सभी को दिल्ली दरबार के बाहर करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो चलेगा नहीं। धरती से लेकर आकाश तक के सारे ठाकुर राजा मांडा की तरफ अगर शरीर से नहीं, तो आत्मा से चले गये हैं।" दिल्ली दरबार ने तुरंत कैप्टन सतीश शर्मा की ओर इशारा किया कि अपने कंप्यूटर से पता लगाओ कि कमलापति त्रिपाठी कितना झूठ बोल रहे हैं?" सतीश शर्मा ने कंप्यूटर का बिना कोई बटन दबाये 'हां' में गर्दन हिला दी। दिल्ली दरबार के मन ने एक बार सोचा कि कहीं यह सतीश शर्मा का 'ब्राह्मणत्व' तो नहीं बोल रहा है। लेकिन दूसरे क्षण उन्हें अहसास हुआ कि अरे इसकी बीवी तो विदेशी है। यह कहां से ब्राह्मण हुआ। दिल्ली दरबार चिन्ता में गहराई से डूबें कि उसके पहले ही पं० उमाशंकर दीक्षित अपनी पुत्रवधू शीला दीक्षित के कंधे पर लदकर आ गये, "यों तो यह कमलापति त्रिपाठी कई घाटों का पानी पिये हुए है। लेकिन बुढ़ापे में औलाद (लल्लू) का मोह इसको सीधे रास्ते पर ले आया है। आपने अच्छा किया कि वीर बहादुर को आइना दिखा दिया। वह अपना भतीजा है, गोपी (गोपीनाथ दीक्षित)...।" कमलापतिजी के करीब बैठे लल्लू का मुंह गोपीनाथ दीक्षित का नाम सुनते ही सूख गया। शीला दीक्षित ने तुरंत अपने ससुर को चुटकी काटकर इशारा किया, "यह मौका गोपी दद्दू के बारे में कुछ कहने का नहीं है।" दीक्षितजी ने बात पलट दी, "कमलापति ठीक कह रहे हैं। हमारे पुराने बचपन के दोस्त द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भी यही कहलाया कि आपका ग्वालियर जाना ठीक नहीं होगा। हमारे समाजवादी मुखौटे पर गहरी आंच आयेगी।" केसरीजी लपक कर आ गये, "पंडितों की राय तो जन्म से मौत तक मानी जाती है। हुजूर, आप ग्वालियर जाकर काहे को फिजूल के चक्कर में फंस रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रजवाड़े हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।" दिल्ली दरबार काफी ऊहापोह में फंसे ही थे कि संसदीय कार्यमंत्रालय अपने सिर पर उठाये एच०के०एल० भगत आ धमके। वह पहले शीला दीक्षित पर बरसे, "तुम यहां बुढ़ऊ को लादे खड़ी हो और वहां संसद में विरोधी दल मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। अविश्वास का प्रस्ताव ले आये हैं।" शीला दीक्षित कोई भबकी दें कि उसके पहले भगतजी की आंख के 'फोकस' में दिल्ली दरबार चिन्ता में डूबता-उतराता आ गया। भगतजी ने अपना मुंह दिल्ली दरबार के कान में संटा दिया, "सर, आपको विरोधी दलों के साथ एक मुचैटा लेना पड़ेगा। वे लोग हम लोगों के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग उनको ऐसा कतई करने नहीं देंगे।" दिल्ली दरबार ने मुस्करा कर कहा, "विरोधी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाकर मेरा क्या उखाड़ लेंगे। हमारे चार सौ से ऊपर प्यादों को कहो कि वे विरोधी दल पर चढ़ बैठें और हाथ-पैर तोड़ डालें। मैं उनसे मुचैटा लेने क्यों जाऊं?" भगतजी ने तुरंत जवाब दिया, "सर उसका पूरा इन्तजाम कर दिया है। आपको तो केवल रस्म-अदायगी के लिए मुचैटा लेना है। हम विरोधी दलों को दिखा देना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली दरबार बोलना भी जानते हैं।" दिल्ली दरबार ने भगतजी के थोबड़े को अपने कानों से अलग करते हुए कहा, "ठीक है, ठीक है। मेरे बोलने की तैयारी कराओ। मैं बोलूंगा।" दूसरे ही क्षण वह फिर कमलापति त्रिपाठीजी की तरफ मुखातिब हो लिये, "पंडितजी आपकी बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। चूंकि सतीश शर्मा कह रहा है कि कंप्यूटर भी वही बोल रहा है जो आप कह रहे हैं, इसलिए मैं ग्वालियर न जाने पर सोच रहा हूं।" इसी समय जार्ज भागा-भागा आया और उसने दिल्ली दरबार के हाथ में आइना थमाते हुए कहा, "सर इसकी चेतावनी को साफ-साफ पढ़ लें। आइना दूसरों को दिखायें, खुद कतई न देखें।" दिल्ली दरबार सांस रोकर आइने की चेतावनी पढ़ ही रहे थे कि पीछे से कमलापति त्रिपाठी उसमें झांक बैठे। कमलापतिजी ने जैसे ही आइने में अपनी आकृति देखी, वह भय से कांपने लगे। कमलापतिजी के आगे-पीछे का सब कुछ उनके चेहरे पर आकर दिखने लगा। वह दरबार स तुरंत लल्लू को लेकर रफूचक्कर हो गये। उमाशंकर दीक्षित दूर से ही भांप गये, तो वह भी शीला दीक्षित के कंधे पर लदकर तुरंत दरबार से फूट लिये। जब 'चेतावनी' पढ़ने के बाद दिल्ली दरबार ने इधर-उधर देखा तो पूरे दरबार में सन्नाटा था। दिल्ली दरबार ने 'इंटरकाम' से तुरंत जार्ज को पूछा कि 'अचानक यह मेरा पूरा दरबार क्यों खाली हो गया?' जार्ज ने अनमने ढंग से जवाब दिया, "सर पता नहीं।" उसके बाद भय से जार्ज ने 'इंटरकाम' काट दिया। इसी बीच दिल्ली दरबार बुरी तरह भयभीत होकर चीख पड़ा। लोग दौड़े। दरबार में कोहराम मच गया। जार्ज ने तुरंत भांप लिया। दिल्ली दरबार ने चेतावनी के बांवजूद लगते [illegible] आइना देख लिया। •

—दर[illegible]

नये साल—१९८८ का सूरज जब नयी रोशनी लेकर दिल्ली दरबार पहुंचा, तो उसे तुरंत लौटा दिया गया, "बाबा कोई और घर देखो। यहां सूखा पड़ा हुआ है। देने को कुछ नहीं है।" नये साल का सूरज मुस्करा कर लौट लिया। लेकिन चोर चोरी से जाता है, हेराफेरी से नहीं। जाते-जाते उसकी कुछ किरणें दिल्ली दरबार को छेड़ ही गयीं। सूरज की किरणों का छेड़ना था कि पूरे दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया।

चहेते महामंत्री नबी !

इंका के अधिकृत प्रवक्ता और पार्टी के महामंत्री गुलाम नबी आजाद की आजकल दूसरे महामंत्रियों नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, केदार नाथ सिंह तथा राम रतन राम से अंदर ही अंदर काफी खींचतान चल रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि गुलाम नबी आजाद के एक पत्रकार मित्र ने पिछले दिनों पार्टी के २४, अकबर रोड स्थित मुख्यालय में नरेश चन्द्र चतुर्वेदी को एक समाचार के मामले में बहुत खरी-खोटी सुनायी। चतुर्वेदीजी इस बात से इतने दुखी हुए कि उन्होंने दूसरे पत्रकारों से यह कह कर बात करना बंद कर दिया कि गुलाम नबी आजाद के इस मित्र पत्रकार के बारे में जब तक वह प्रधानमंत्री राजीव गांधी से 'दो-टूक' बात नहीं कर लेंगे, तब तक किसी भी पत्रकार से नहीं बोलेंगे।

बताया जाता है कि चतुर्वेदीजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जब इस पत्रकार के बारे में बात करने के लिए गये, तो उलटे राजीव गांधी ने चतुर्वेदीजी को जमकर फटकार लगा दी कि जो पत्रकार हमारी मदद कर रहे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत खराब है। अगर भविष्य में ऐसा हुआ, तो मुझे आपको 'प्रेस' से बात करने के लिए मना ही कर देना पड़ेगा। राजीव गांधी ने चतुर्वेदीजी की एक बात नहीं सुनी। वह बहुत दुखी होकर लौटे, तो पत्रकारों को उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि यह गुलाम नबी आजाद मेरे खिलाफ राजीव गांधी से समय-समय पर बहुत कुछ कहता रहता है।

[illegible]या जाता है कि चतुर्वेदीजी ने [illegible] वरिष्ठ नेता पं० उमाशंकर दीक्षित से भी गुलाम नबी आजाद की शिकायत की, लेकिन दीक्षितजी का कहना था कि इसके लिए वह उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी राजीव गांधी का खास चहेता है।

पिछले दिनों इंका महामंत्री केदार नाथ सिंह ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री सचिवालय से फोन करके मना कर दिया गया। उनको बताया गया कि फेयरफैक्स के बारे में पार्टी की ओर से बोलने के लिए केवल गुलाम नबी आजाद को ही अधिकृत किया गया है। इसके पहले भी केदारनाथ सिंह को कई बार गुलाम नबी आजाद के इशारे पर प्रेस से बोलने की मनाही हो चुकी है। केदारनाथ सिंह का कहना है कि यह सब गुलाम नबी ही करा रहा है, लेकिन वह गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। भोपाल से लौटने के बाद राम रतन राम की स्थिति तो काफी खराब हो ही गयी थी। मास्को से लौटने के बाद उसे और खराब कर दिया गया। वह गुलाम नबी आजाद के सामने पूरी तरह हथियार डाले हुए हैं।

राजीव गांधी ने अभी पिछले दिनों इंका के महामंत्रियों के कामों की समीक्षा की। मूपनार को तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन तीन महामंत्रियों के काम-काज की कड़े शब्दों में आलोचना की गयी। ये महामंत्री थे—नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह और राम रतन राम। गुलाम नबी आजाद समीक्षा के दौरान पूरी तरह छाये रहे। कहा जाता है कि इन तीन महामंत्रियों को राजीव गांधी से डांट पड़वाने के पीछे भी गुलाम नबी आजाद का ही हाथ था, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ये लोग गुलाम नबी आजाद के खिलाफ चूं भी नहीं कर पा रहे हैं।

मुकाबला टल गया

प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच १४ दिसंबर को राज्य सभा में ठक्कर-नटराजन आयोग पर हुई बहस में सीधी टक्कर होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी और खान-इस्पात मंत्री माखनलाल फोतेदार ने उसे टलवा दिया।

बताया जाता है कि १४ दिसंबर की सुबह जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बताया कि ठक्कर-नटराजन आयोग पर राज्यसभा में होंने वाली बहस का वह उत्तर देंगे, तो नारायण दत्त तिवारी और फोतेदार ने उनको अलग ले जाकर मनाया कि अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ परेशानी में डालने वाले प्रश्न पूछे तो फिर क्या होगा? राजीव गांधी ने जवाब दिया कि मैं उनका उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की सलाह है, तो मैं फेयरफैक्स की बहस में हिस्सा ही न लूंगा।

अंत में राजीव गांधी संसद के दोनों सदनों में १४ दिसंबर को ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पर हुई बहस में शामिल नहीं हुए और राजीव गांधी तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच होने वाली टक्कर नहीं हो पायी।

अपने प्रदेश की चिंता

प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने गृह राज्य (उ०प्र०) की बहुत चिंता है, क्योंकि वहां लोकसभा की ८५ सीटें हैं।

बर्मा की यात्रा पर १५ दिसंबर को रवाना होने के पूर्व राजीव गांधी से इंकाई सांसदों के कई प्रतिनिधिमंडल मिले। उनमें से एक था महाराष्ट्र के इंकाई सांसदों का। इन सासंदों में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री वसंत साठे और परिवार नियोजन राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे भी थीं। वैसे तो इस प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र की कपास समस्या पर प्रधानमंत्री से बातचीत की, लेकिन चलते-चलते कुछ सांसदों ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत शुरू कर दी। वसंत साठे और सरोज ने इस बातचीत से तुरंत अपने को अलग कर लिया और वे दोनों बाहर चले आये।

इंकाई सांसदों को राजीव गांधी ने बताया, "मैंने मुख्यमंत्री एस०बी० चह्वाण को मंत्रिमंडल के विस्तार की अनुमति नहीं दी है। अगर वह अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन कर लेते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।" इसी के साथ राजीव गांधी ने इंकाई सांसदों को बताया, "महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष प्रभा राव का कामकाज संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें हटाया जा सकता है।"

जब महाराष्ट्र के कुछ इंकाई सासंदों ने मुख्यमंत्री चह्वाण के हटाये जाने का प्रश्न उठाया और कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो राजीव गांधी ने तपाक से कहा, "आपको अपने राज्य की चिंता है और मुझे अपने राज्य (उ०प्र०) की चिंता है। आपके प्रदेश से मेरा उ०प्र० काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से लोकसभा की ८५ सीटें हैं। पहले मैं अपने उ०प्र० को ठीक कर लूं, उसके बाद आपके प्रदेश पर ध्यान दे पाऊंगा। इतनी जल्दी आप लोग न करें।" महाराष्ट्र के इंकाई सांसद यह मानकर बाहर चले आये कि राजीव गांधी अपने गृह राज्य उ०प्र० को ठीक करने के बाद महाराष्ट्र के बारे में विचार करेंगे।

इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ के पुत्र प्रिंस चार्ल्स की शादी जिस भव्यता, राजशाही गरिमा और परंपरा के साथ जब डायना से हुई थी, उस समय विश्व के हर कोने से विशेष और सामान्य मेहमानों का तांता लंदन पहुंचा था। उसी तर्ज पर रेलराज्यमंत्री माधवराव सिंधिया ने कश्मीर रियासत के पूर्व महाराजा कर्ण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से अपनी पुत्री राजकुमारी चित्रांगदा की ११ दिसंबर, १९८७ को ग्वालियर में शादी का आयोजन किया। यह परिणय-पर्व लगभग तीस हजार लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। और इसी के साथ कश्मीर और ग्वालियर की पूर्व रियासतें एक दूसरे की रिश्तेदार हो गयीं। शादी की भव्यता के बारे में कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला का कहना है कि वह जिंदगी में दूसरी बार ऐसी भव्यता देख रहे हैं। पहली बार ऐसी भव्यता कर्ण सिंह की शादी पर देखी थी और इस बार उनके पुत्र की शादी पर। शादी के अवसर पर माधवराव सिंधिया के निवास 'जय विलास पैलेस' को आलीशान ढंग से सजाया गया था। महल के सामने ही विवाह मंडप बनाया गया था। विवाह की सभी रस्में पारंपरिक रीति-रिवाज से सिंधिया घराने के राजपुरोहितों ने संपन्न करायीं। बारात की अगवानी माधवराव सिंधिया, उनके पुत्र और उनकी मां विजयाराजे सिंधिया ने की। १९८४ के चुनाव से पुत्र-मां का जो अलगाव हुआ था, उसका मिलन इस अवसर पर देखने के लिए भी लोगों की आंखें बिछी हुई थीं।

भव्यता और राजशाही गौरव की इस शादी में भोज नहीं दिया गया। मेहमानों के लिए सिर्फ चाय और काफी का इंतजाम था, इसके बावजूद लोगों का कयास है कि इस शादी पर ३० करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन यह तथ्य है कि इस शादी में ग्वालियर की सारी जनता ने भाग लिया और अपने स्तर पर भी ग्वालियर को सजाया-चमकाया।

बारात के स्वागत के लिए खड़े माधवराव सिंधिया एवं उनके पुत्र ज्योतिरादित्य

'जय विलास महल' का झिलमिलाता

दूल्हा विक्रमादित्य राजघराने की बग्घी में

कर्ण सिंह और फारूख अब्दुल्ला बारात में

111155

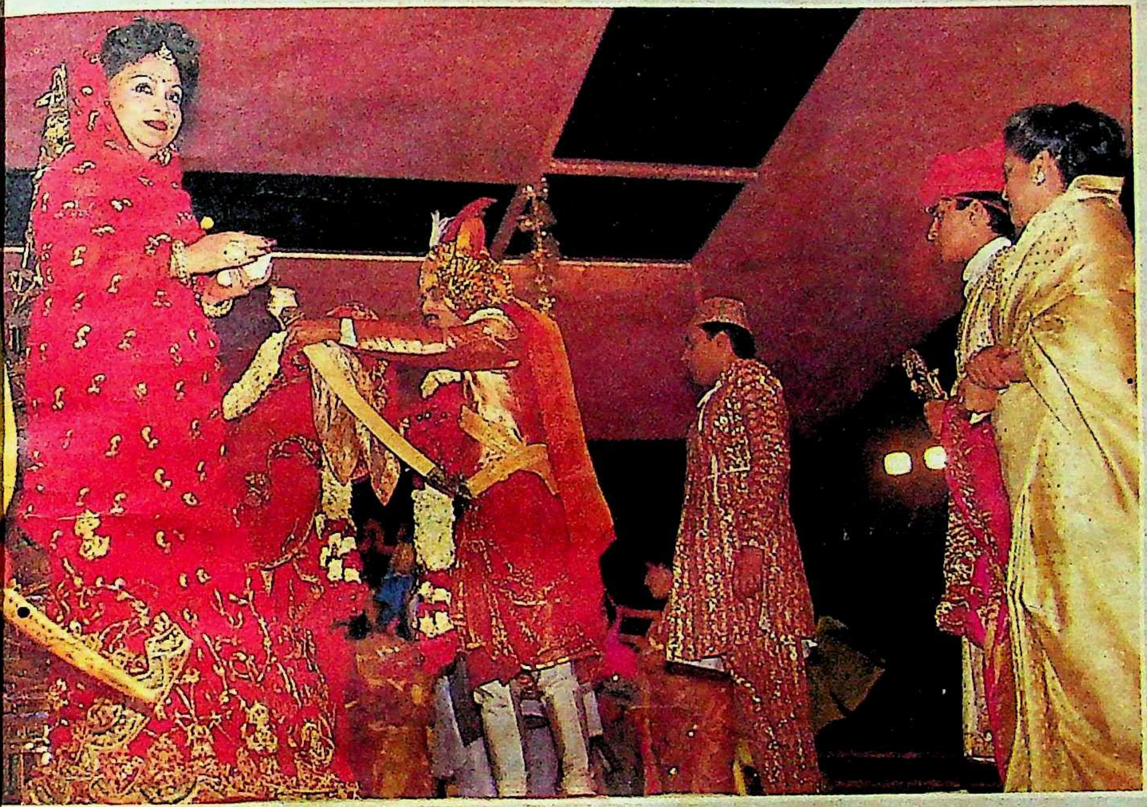

जयमाला पहनाते हुए राजकुमार विक्रमादित्य और राजकुमारी चित्रांगदा

माधवराव सिंधिया विवाह मंडप में
वर और वधू के साथ

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
अतिथियों का स्वागत करते हुए

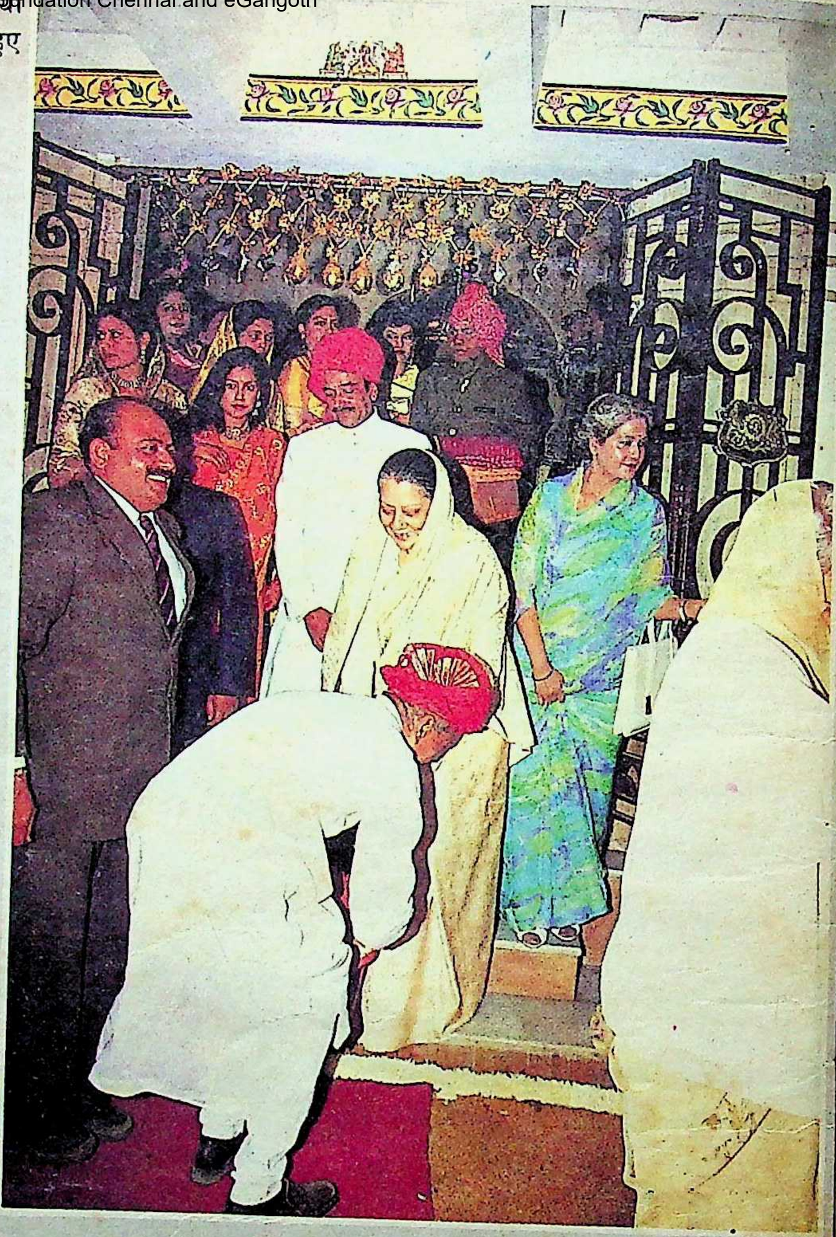

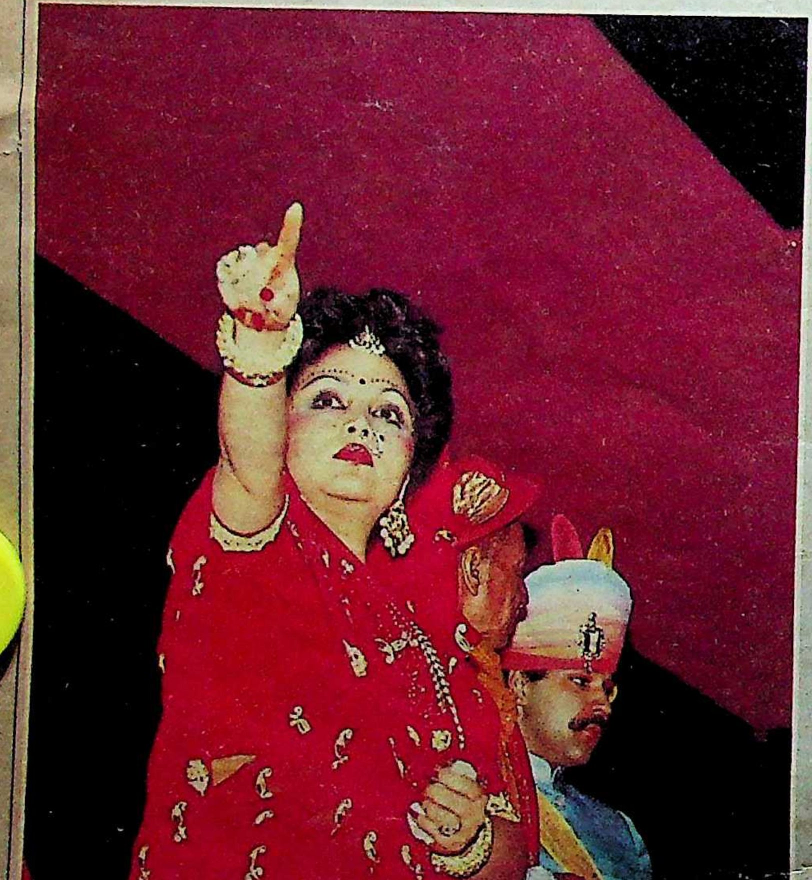

विवाह मंडप में
श्रीमती माधवी राजे सिंधिया

छाया : सुनील सक्सेना

एक अभूतपूर्व शादी

वधू चित्रांगदा और वर विक्रमादित्य

११ दिसम्बर को ग्वालियर के भूतपूर्व महाराज माधवराव सिंधिया की पुत्री चित्रांगदा राजे और जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व सदरे रियासत डा० कर्ण सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य की शादी की भव्यता के बारे में कहा जाता है कि आजादी के बाद ऐसी आलीशान शादी कभी देखने को नहीं मिली। यह शादी किस तरह संपन्न हुई?

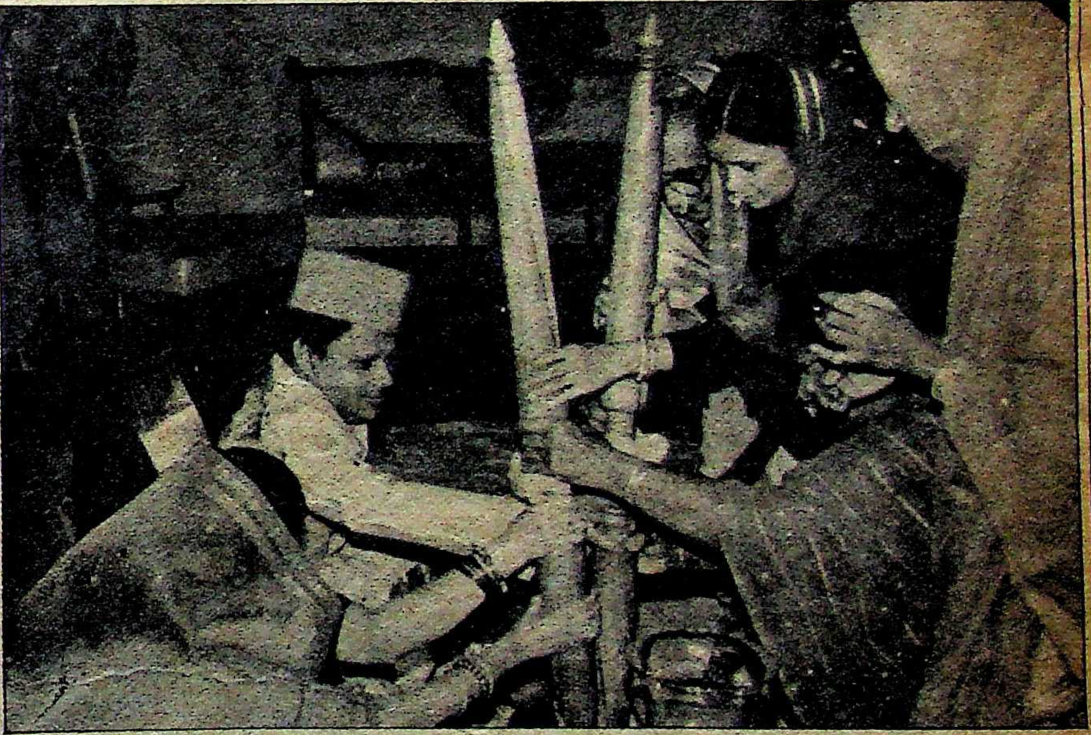

पिता के रूप में रस्म अदायगी करते माधवराव सिंधिया

वैभव ऐश्वर्य के बिना शाही घरानों में रस्मो-रिवाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ११ दिसंबर को ग्वालियर में सिंधिया राजवंश के जयविलास प्रासाद में ग्वालियर के भूतपूर्व महाराज व वर्तमान केंद्रीय रेलराज्यमंत्री माधवराव सिंधिया की बेटी चित्रांगदा राजे और जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत के प्रमुख तथा राज्य के पूर्व राज्यपाल डा० कर्ण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के विवाह के अवसर पर भी वैभव व ऐश्वर्य के नजारे देखने को मिले।

हालांकि श्री सिंधिया प्रारंभ से लेकर अंत तक यह कहते रहे कि बेटी का विवाह उनका निजी पारिवारिक प्रसंग है और इसे वह सार्वजनिक जलसा नहीं बनाना चाहते, किंतु सामंती काल की शेष बची जन-प्रवृत्तियों तथा अन्य अनेक इतर कारणों से यह शाही विवाह अचर्चित नहीं रह सका। और तो और भरसक कोशिशों के बावजूद सिंधिया आरोपों के घेरे में आने से भी नहीं बच सके।

सिंधिया घराने में हुई इस शादी के महत्व व इसकी व्यापक तैयारियो का अदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तीन अलग-अलग तरह के निमंत्रण पत्र २५ से ५० हजार के बीच लोगों को भेजे गये। देश की सभी भूतपूर्व रियासतों व रजवाडों को न्यौते भेजे गये। सिंधिया ने न केवल प्रमुख घरानों को निमंत्रण भेजा, बल्कि परंपरा व गरिमा का पालन करते हुए हाथ से लिखकर पातीं या चिट्ठी भी भेजी। एक अनुमान के अनुसार राजघरानों की इस खर्चीली शादी में २० से ३० करोड़ के बीच रुपए खर्च किये गये। यह तय नहीं है कि यह सिंधिया का स्वयं का निर्णय था या उनके सलाहकारों का परामर्श कि प्रेस को प्रारंभ में कार्यक्रम से दूर रखने का निर्णय किया गया था, लेकिन बाद में क्षोभ व रोष को देखकर यह फैसला बदलना पड़ा। नतीजतन, ११ दिसंबर को सौ से भी अधिक पत्रकार विवाह स्थल पर मौजूद थे।

डोगरा और सिंधिया घरानों के बीच हुआ ये विवाह संबंध मेहमानों के कारण भी चर्चा का विषय रहा। नेपाल नरेश महाराज बीरेंद्र विक्रम शाह विशेष तौर पर ग्वालियर आये। शाही विवाह में शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी आने की जोर-शोर से चर्चा थी और उनके आगमन के सिलसिले में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की थीं। बताते हैं कि प्रधानमंत्री का पूरा प्रोग्राम भी तैयार होकर आ गया था और यह भी तय हो गया था कि वह जयविलास पैलेस में विशेष तौर पर स्थित निमित बुलेटप्रूफ बाक्स में बैठकर शादी का नजारा देखेंगे तथा फिर भोपाल लौट जायेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की संभावना से पुलिस व प्रशासन में चुस्ती आना स्वाभाविक था, किंतु १० दिसंबर की शाम तक यह तय हो चला था कि प्रधानमंत्री नहीं आयेंगे। प्रधानमंत्री के न आने से बहुतों को निराशा हुई और सुरक्षा अमले ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस तथा भोपाल में व्यस्त प्रोग्राम के कारण नहीं आये, तो कुछ का मत है कि प्रधानमंत्री ने एक शाही शादी में शरीक होकर एक नये विवाद को जन्म देना उचित नहीं समझा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सगाई

तन्दुरुस्ती के
संग-संग, अब
...ताज़गी भी!

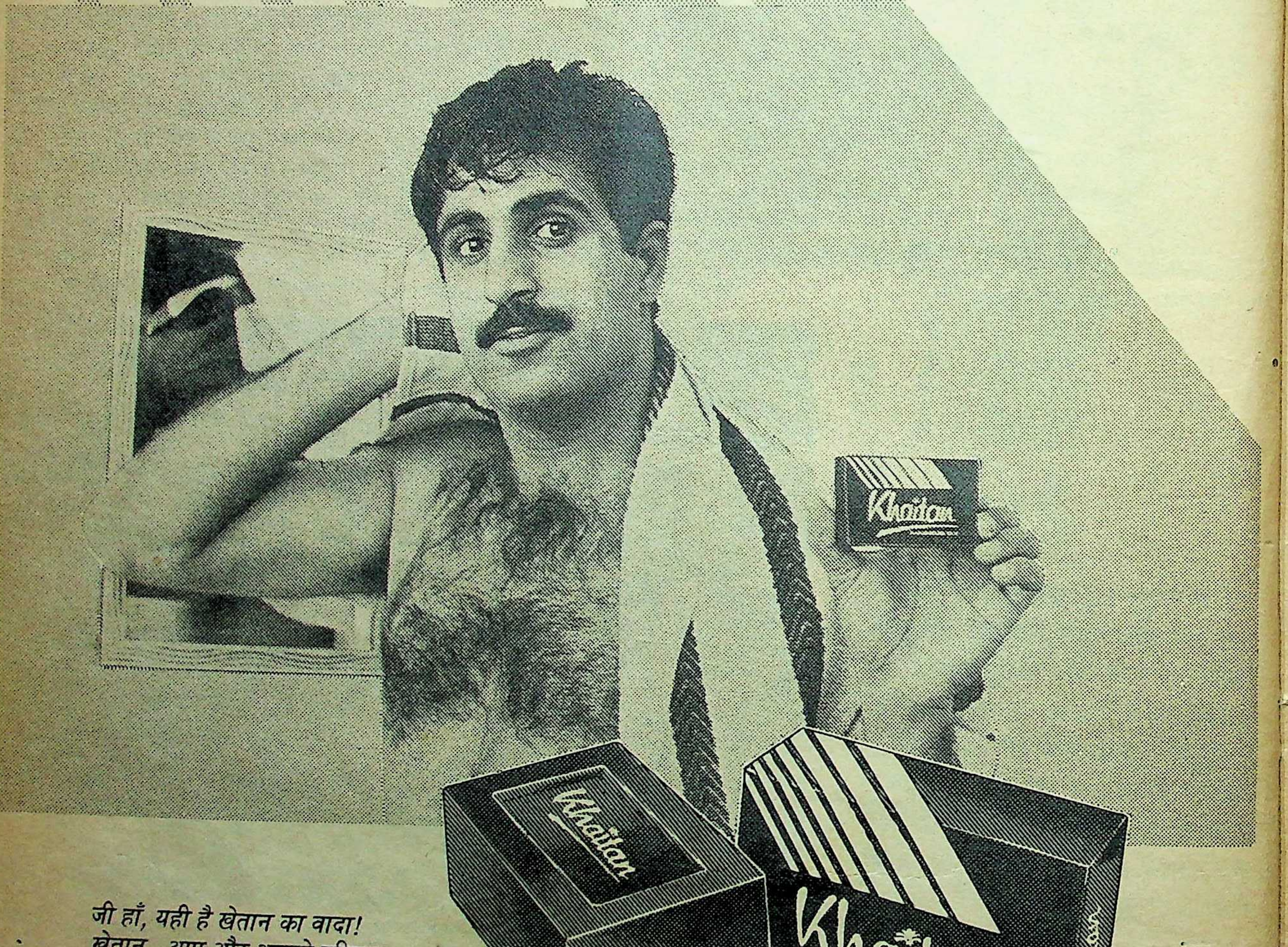
Khaitan
Khaitan
Khaitan
THE COMPLETE SOAP
Khaitan

*जी हाँ, यही है खेतान का वादा!
खेतान...आप और आपके परिवार
के लिए बनाया गया एक ऐसा
नहाने का साबुन जो न सिर्फ़
आपको तन्दुरुस्त रखता है,
बल्कि दिन भर तरोताज़ा भी.*

आज ही आज़माईये!

खेतान
एक सम्पूर्ण साबुन

naa/ND/KCL/87

एक सम्पूर्ण साबुन... पूरे परिवार के लिये!

खेतान केमिकल्स लिमिटेड का एक उत्कृष्ट उत्पादन

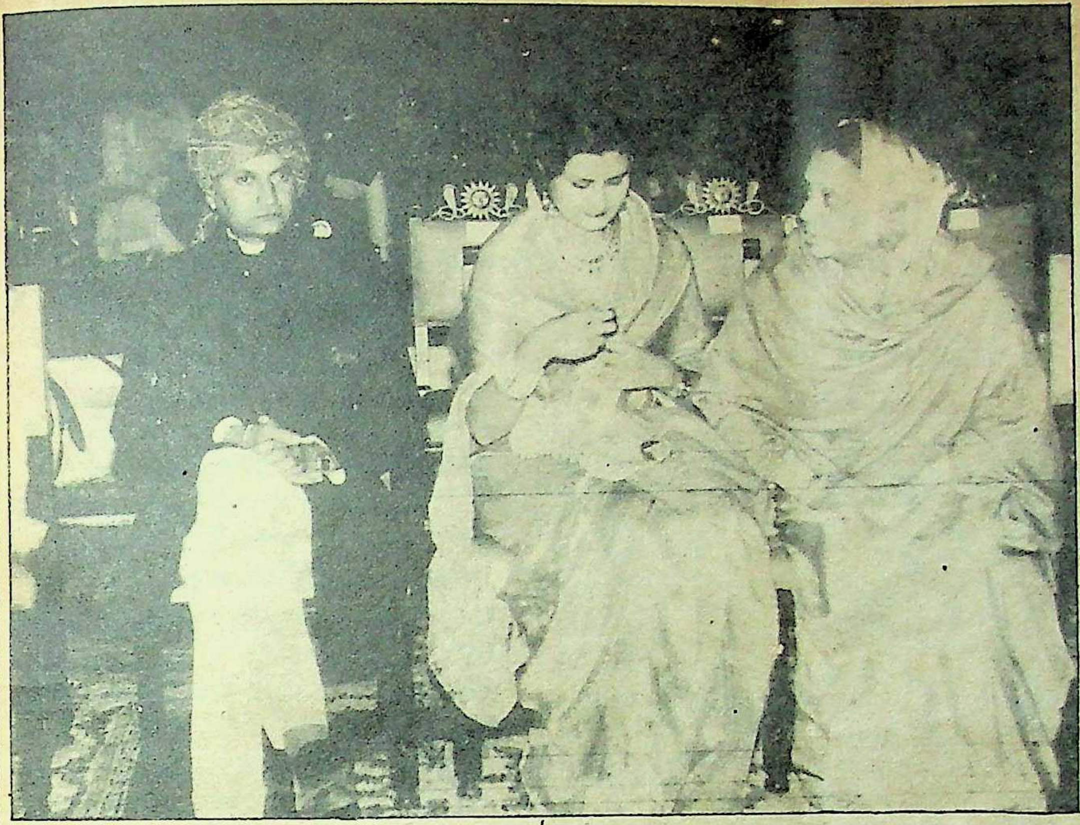

उपेक्षित: राजमाता सिंधिया उन कुरसियों पर जिन पर राजचिन्ह जड़ा है

समारोह में प्रधानमंत्री राजीव सोनिया के साथ आये थे।

प्रधानमंत्री के न आने और भोपाल में रात्रि प्रवास का परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री समेत कोई भी मंत्री शादी में शरीक नहीं हो सका। केवल दो, शिक्षा राज्य मंत्री चित्रकांत जायसवाल व संसदीय सचिव महेंद्र बोद्ध ही वहां नजर आये। मुख्यमंत्री वोरा व विधानसभा अध्यक्ष शुक्ल दोपहर में नेपाल नरेश की अगवानी के लिए आये और फिर भोपाल लौट गये। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सांसदों की टोली शाही शादी में शरीक होने से वंचित रही। महाराज सिंधिया को मिला लें, तो कुल जमा पांच सांसद-सिंधिया, महेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह, गायकवाड़ व बलराम सिंह यादव ही वहां थे। राज्यसभा सदस्यों में पी० उपेंद्र, आशीष सेन, सईदा खातून, वीणा वर्मा, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, रिछारिया आदि उपस्थित थे। पूर्व में साठ सांसदों के आने की पक्की सूचना थी और उनके लिए कमरे आरक्षित थे।

उद्योगपति व राजे-महाराजे: मंत्रियों व सांसदों से हीन जमावड़े में उद्योगपति व पूर्व राजे-महाराजे बड़ी संख्या में शरीक हुए। देश के चोटी के उद्योगपति-नसली वाडिया, किर्लोस्कर, आदित्य बिड़ला, गरवारे और मंडेलिया आदि शादी में शरीक होने आये। स्थिति यह थी कि ग्वालियर में सभी होटल, लाज, रेस्ट व गेस्ट हाउस कई रोज पहले से आरक्षित हो गये थे। फलत: बहुतों को अपने दोस्तों व नातेदारों के यहां शरण लेनी पड़ी। इस सामंती शादी से एक और काम यह हुआ कि करीब तीन दशकों के बाद जयविलास पैलेस की साफ-सफायी व रंग-रोगन हो गया। दरबार हाल से लेकर बाहर लगी तोप तक को चमकाया गया और सिंधिया घराने की अत्यंत प्रसिद्ध शरांब परोसनेवाली सात बोगियों की खिलौना रेलगाड़ी के चक्के विशिष्ट अतिथियों के लिए घूमे। साढ़े तीन टन और ढाई सौ बल्बों के झाड़-फानूस को इस मौके के लिए नयी चमक प्रदान की गयी।

विवाह संस्कार व उसकी तैयारियों के दौरान यह पढ़ने व सुनने को मिला कि महाराज के नाम पर शहर में भारी-भरकम चंदा हुआ। इस बारे में महाराज के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि महाराज ने अपनी ओर से किसी से कुछ नहीं कहा। समाचारपत्रों में प्रकाशित सबको आमत्रण में स्पष्ट तौर पर उल्लेख था कि इस अवसर पर कोई भेंट स्वीकार नहीं की जायेगी, आपका आशीर्वाद ही यथेष्ट है। लेकिन विशेष सूत्रों के अनुसार खुद श्री सिंधिया ने अपने विश्वासपात्रों की एक उपहार समिति बनायी। सिंधिया स्कूल के उप प्रधानाचार्य देवी शंकर शर्मा उपहार समिति के संयोजक थे। महल के अतिविश्वासपात्र और ईमानदार समझे जाने वाले लोगों को इसमें रखा गया। इस चमक-दमक और शाही शादी को देखने के लिए ११ दिसंबर को एक तरह से समूचा ग्वालियर ही उमड़ पड़ा और बारात गुजरने के रास्तों पर मेले-सा दृश्य उपस्थित हो गया।

—सुधीर सक्सेना

राजमाता बनाम माधवराव

इस अपव्यय से मैं शर्मिंदा हूं

चित्रांगदा राजे और विक्रमादित्य के विवाह के अवसर पर मां और बेटे के बीच मनमुटाव की एक बार फिर पुष्टि हुई। विवाह के अवसर पर छपे किसी भी निमंत्रण पत्र में राजमाता का नाम नहीं था और बताते हैं कि इससे उन्हें मर्मान्तक पीड़ा हुई। सिंधिया घराने में वरिष्ठतम होने के नाते राजमाता को काफी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन राजमाता शादी के एक दिन पूर्व १० दिसंबर को आयीं। उनकी तीनों पुत्रियां—उषा, वसुंधरा और यशोधरा भी इसी दिन आयीं। राजमाता अपने दामादों—राणा शमशेर जंग व डा० भंसाली को लेने खुद हवाई अड्डे गयीं।

संपूर्ण प्रसंग से राजमाता कितनी दुखी थीं, इसका पता १२ दिसंबर को उनसे मुलाकात में चला। उन्होंने कहा कि माधव से उनके मतभेद हैं, लेकिन पोती ने उनका क्या बिगाड़ा है कि वह उसे आशीर्वाद देने न जातीं। माधवराव ने पुत्री के विवाह के मौके पर जिस वैभव का प्रदर्शन किया है, उसके पीछे पिता या महाराजा की भावना कम केंद्रीय मंत्री की भावना ज्यादा थी। उसने ट्रस्ट की संपत्ति का निजी उपयोग किया। ग्वालियर की जनता ने तो आत्मीयता व श्रद्धा का परिचय दिया, किंतु उनके बेटे ने जनता की भावनाओं का शोषण ही किया।

जानकार सूत्रों के अनुसार माधवराव ने ४ दिसंबर को मां को फोन कर आने को कहा था, लेकिन राजमाता का कहना है कि उन्हें तो शादी की सूचना तब मिली, जब भाजपा ने उनकी गिरफ्तारी देने की तारीख तय कर दी थी। राजमाता ने कहा, "बेटे ने धर्मसंकट में डाला था, भाजपा ने धर्मसंकट से बचा लिया।" सच तो यह है कि माधवराव सिंधिया ने सिंधिया जैसा बर्ताव नहीं किया। उसके पिता ने राज संपत्ति का ५५ करोड़ रुपया इस लिये दिया था कि वह जनता के काम आये, किंतु माधव ने योजना के तहत ट्रस्टों से मुझे हटाकर ट्रस्ट की रक़म का दुरुपयोग किया। इसे जनधन के निर्मम अपव्यय की संज्ञा देते हुए राजमाता ने कहा, "मैं तो शर्मिंदा हूं। पता नहीं उसे अफसोस है या नहीं।".

बातचीत में राजमाता ने प्रधानमंत्री के न आने पर टिप्पणी की, "राजीव गांधी को भोपाल में कलेक्टरों के साथ खाना खाने की फुर्सत थी, लेकिन इतना समय नहीं था कि भोपाल से ग्वालियर आकर नवदंपति को आशीर्वाद देते।"

—सुधीर सक्सेना

पिछला साल कैसे गुजरा ?

गुजरा साल घटनाओं का एक जमघट मात्र नहीं, बल्कि इतिहास के अनंत विस्तार का एक अटूट अंग है, जिसमें आनंद का अमृत, वेदना का विष दोनों मौजूद होता है। इसलिए अतीत की स्मृति काट-पोंछकर मिटायी नहीं जाती, वर्तमान से जोड़कर भविष्य के समुचित उपयोग के लिए संजोयी जाती है। पेश हैं, देश के पिछले वर्ष की अहम घटनाएं:

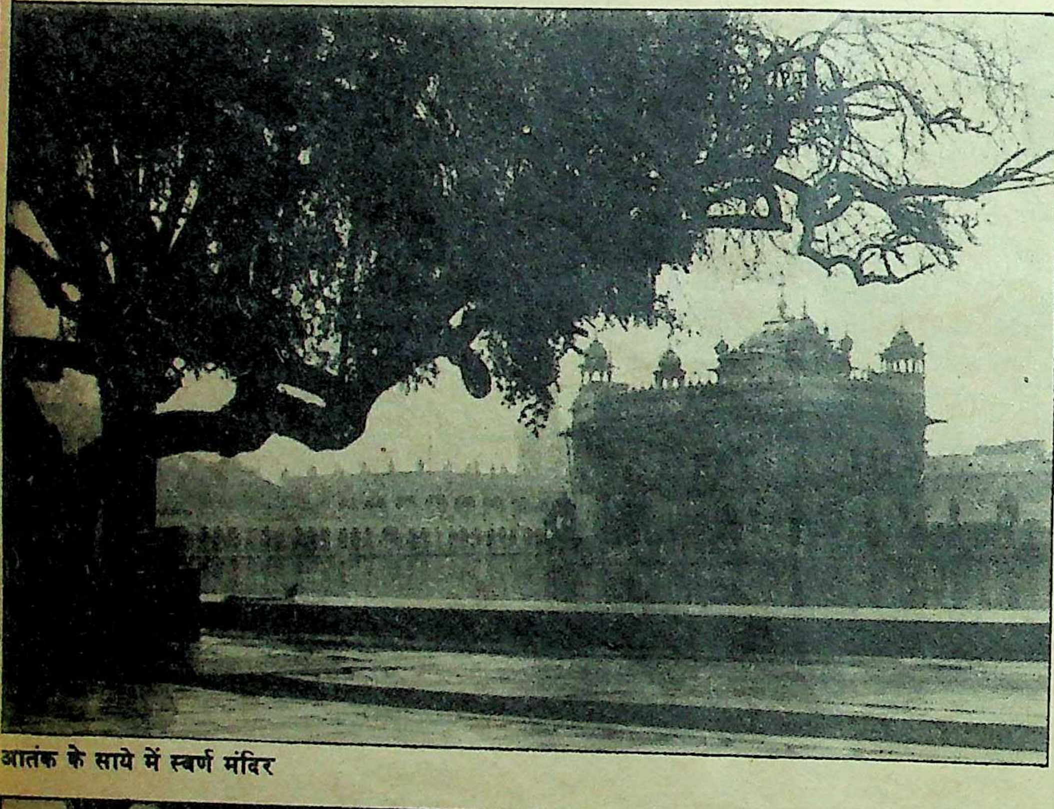
आतंक के साये में स्वर्ण मंदिर

रागी द्वारा अकाली दलों की एकता के लिए सभी गुटों को भंग करने की घोषणा

२ जनवरी, १९८७: उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योगमंत्री रह चुके हरेकृष्ण महताब का निधन।

६ जनवरी, ८७: इंदिरा भक्तों द्वारा पूर्व वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन। 'हम दोनों' 'रेशमा शेरा' जैसी दर्जनों यादगार फिल्मों के प्रख्यात संगीत निर्देशक जयदेव का निधन।

८ जनवरी: युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित रंगभेद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय युवक अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा।

९ जनवरी: आतंकवादियों द्वारा पंजाब के विभिन्न इलाकों में २४ घंटों में ११ निरीह लोगों की निर्मम हत्या।

१० जनवरी: ११वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री पाल श्लुटर का भारत आगमन।

१४ जनवरी: उ०प्र० के पूर्व मंत्री जयराम वर्मा का निधन।

१५ जनवरी: राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर सरकार से सफायी की मांग।

आतंकवादियों द्वारा कर्नल संत सिंह भुल्लर सहित ४ की हत्या।

१६ जनवरी: केरल के पूर्व राज्यपाल के० विश्वनाथन का निधन। प्रधानमंत्री द्वारा बरनाला से भेंट के बाद पंजाब मसले के हल के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित।

१७ जनवरी: दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ में तीन मरे।

१८ जनवरी: स्वर्ण मंदिर परिसर की तलाशी में ७८ संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। इंदिरा गांधी स्मारक हाकी (दिल्ली) में हालैंड चैंपियन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त लोकदल में शामिल।

१९ जनवरी: पंजाब प्रदेश इंका महासचिव व पूर्व मंत्री जोगिन्दर पाल पांडे की लुधियाना में आतंकवादियों द्वारा दिनदहाड़े हत्या। उ०प्र० लोकदल अध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा ने पद से इस्तीफा दिया।

२० जनवरी: विदेश सचिव ए०पी० वेंकटेश्वरन का त्यागपत्र।

२१ जनवरी : चीन स्थित भारतीय राजदूत के०पी०एस० मेनन नये विदेश सचिव। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की एक दिन की देशव्यापी हड़ताल।

२२ जनवरी : त्रिपुरा सरकार द्वारा ट्राइबल्स नेशनल वालेंटियर्स (टीएनवी) छापामारों पर प्रतिबंध।

२३ जनवरी : पंजाब सीमा पर सेना तैनात। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा केशगढ़ व दमदमा साहिब के मुख्यग्रंथियों की बर्खास्तगी।

२४ जनवरी : वी०पी० सिंह नये रक्षामंत्री। ब्रह्मदत्त वित्तराज्यमंत्री। अफ्रीकी देशों की सहायतार्थ नयी दिल्ली में अफ्रीका कोष सम्मेलन।

२६ जनवरी : स्वर्ण मंदिर में गणतंत्र दिवस पर सरबत खालसा द्वारा कुछ राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव पारित। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार (मरणोपरान्त) से सम्मानित।

२८ जनवरी : नौगांव (असम) में यात्री बस नदी में गिरने से ६० की मृत्यु।

२९ जनवरी : वयोवृद्ध नेता उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल।

३० जनवरी : इराडी आयोग की पंजाब-हरियाणा के मध्य रावी-व्यास नदी जल वितरण संबंधी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को पेश।

३१ जनवरी : भारत-पाक सीमा विवाद के हल के लिए भारत-पाक विदेश सचिवों की दिल्ली में वार्ता।

१ फरवरी : विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद के मसले पर आयोजित भारत बंद विफल।

३ फरवरी : अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार प्रो० दर्शन सिंह रागी द्वारा अकाली दल में एकता हेतु सभी गुट भंग। रतन थियेम नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के नये निदेशक।

४ फरवरी : भारत-पाक फौजें पीछे हटाने पर सहमत।

५ फरवरी : सिमरनजीत सिंह मान संयुक्त अकाली दल के नये नेता। बरनाला द्वारा प्रो० रागी का हुक्मनामा मानने से इनकार।

८ फरवरी : खुड्डा हत्याकाण्ड का आतंकवादी करमजीत सिंह सुरक्षा बल से मुठभेड़ में मारा गया।

दंगों के बाद कर्फ्यूग्रस्त चांदनी चौक

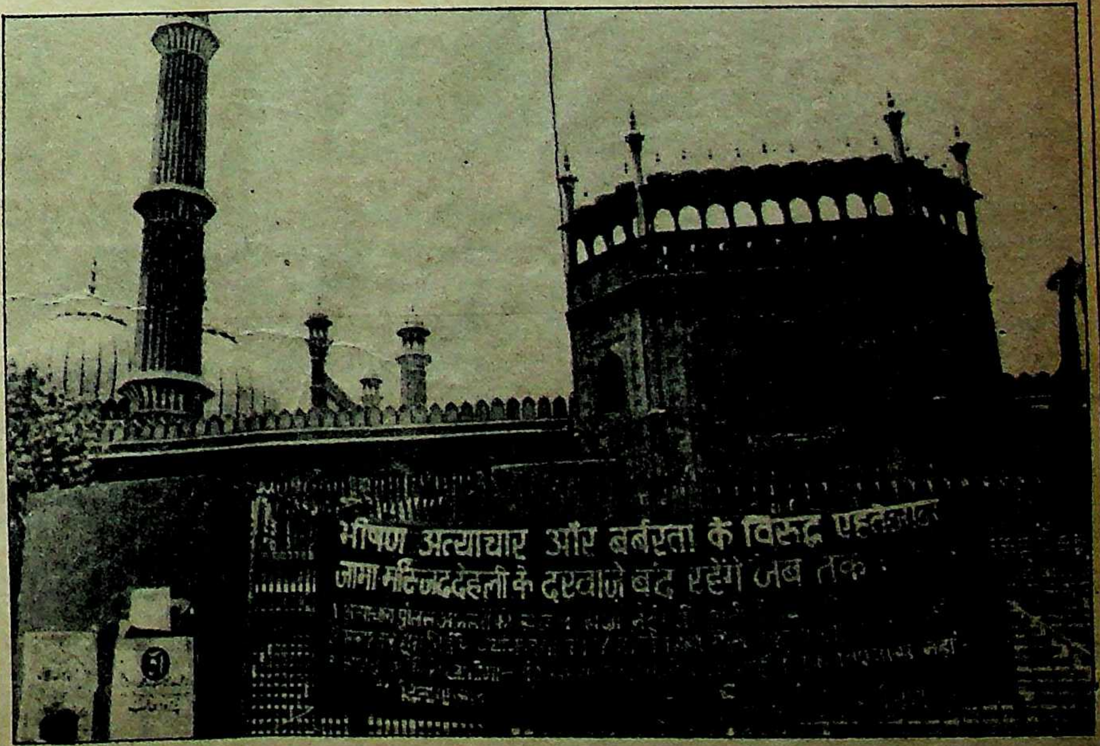
भीषण अत्याचार और बर्बरता के विरुद्ध एहतेजाज
जामा मस्जिद देहली के दरवाजे बंद रहेंगे जब तक

जामा मस्जिद पर ताला

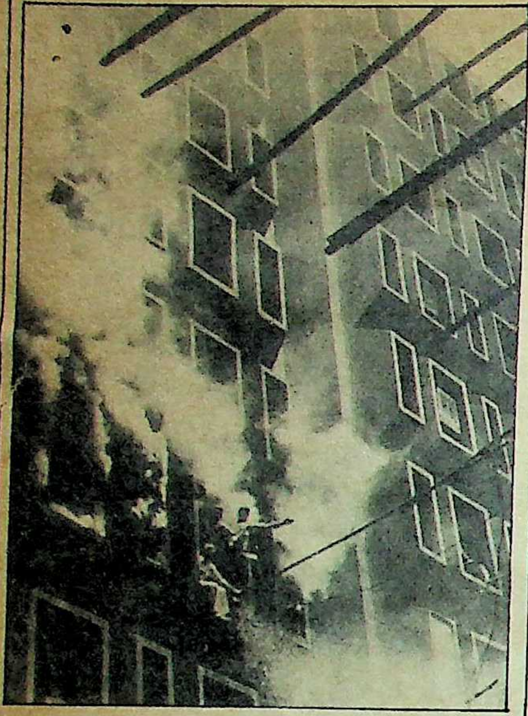

अंसल भवन में आग

९ फरवरी: मुख्यग्रंथी द्वारा बरनाला तनखैया घोषित। डा० एस०आर० श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के नये अध्यक्ष।

१० फरवरी: उ०प्र० विधानसभा में विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव अपने पद से हटाये गये।

११ फरवरी: मुख्यग्रंथियों द्वारा बरनाला को पंथ से निकालने का ऐलान। इंदिरा गांधी हत्याकाण्ड के अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर।

१२ फरवरी: आतंकवादियों ने लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक से पौने छह लाख रु० लूटे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह का निधन।

१३ फरवरी: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम० भक्तवत्सलम का देहान्त। खुड्डा हत्याकाण्ड का सरगना मंजीत सिंह खडाला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

१४ फरवरी: इंदिरा गांधी हत्याकाण्ड के प्रमुख अभियुक्त सतवंत सिंह द्वारा फांसी की सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर।

१८ फरवरी: दिल्ली में ३९वें विश्व टेबिल टेनिस चैंपियनशिप का राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा उद्घाटन। गोपी अरोड़ा प्रधानमंत्री के विशेष सचिव नियुक्त।

२० फरवरी: मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। लालडेंगा को मुख्यमंत्री पद की शपथ।

२१ फरवरी: लोकदल दो धड़ों में विभाजित। पाक राष्ट्रपति जिया क्रिकेट मैच देखने भारत पधारे।

२२ फरवरी: मशहूर कव्वाल हबीब पेन्टर का निधन।

२३ फरवरी: १९८४ के दिल्ली दंगों से संबंधित रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में पुलिस पर सवालिया निशान। हरबंस सिंह धुमन बरनाला के स्थान पर अकाली दल (लोंगोवाल) के नये नेता निर्वाचित।

२६ फरवरी: अजीत सिंह गुट द्वारा पार्टी अध्यक्ष बहुगुणा को हटाकर नये लोकदल-अ का गठन।

४ मार्च: के०एस० हाजी शरीफ फिक्की के नये अध्यक्ष।

५ मार्च: पी०सी० सेठी, ए०पी० शर्मा, श्रीपति मिश्र के मुअत्तली आदेश खारिज।

६ मार्च: ओखला (दिल्ली) के पास दिल्ली-जीटी एक्सप्रेस ने ५ व्यक्ति कुचले।

विदाई: पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह

७ मार्च: अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट में गावस्कर ने १० हजार रन पूरे करके विश्व रिकार्ड बनाया। अजमेर शरीफ के उर्स की भगदड़ में छह मरे।

१० मार्च: आतंकवादियों ने पंजाब में छह लोगों की हत्या की।

११ मार्च: होशियारपुर के एक गुरुद्वारा प्रमुख सहित ५ की आतंकवादियों द्वारा हत्या।

१३ मार्च: इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नाम लिखे गोपनीय पत्र के प्रकाशन पर संसद में हंगामा। गोयनका के यहां केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का छापा।

१५ मार्च: त्रिचनापल्ली (तमिलनाडु) के समीप राकफोर्ट एक्सप्रेस के ८ डिब्बे बम विस्फोट से नदी में गिरे, २५ यात्री मृत। अकाली विधायक अमरजीत सिंह की आतंकवादियों द्वारा हत्या।

१७ मार्च: पंजाब में आतंकवादियों ने भाजपा नेता शंभूप्रसाद सहित १२ लोगों की जान ली। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के पत्र का जवाब। भागलपुर में जहरीली शराब पीने से २५ मरे।

१८ मार्च: पंजाब में छह की हत्या।

२० मार्च: गुजरात में प्रदर्शनकारी किसानों व पुलिस के बीच गोलीबारी में ५ मृत और पूर्व मुख्यमंत्री सोलंकी सहित सैकड़ों घायल।

२४ मार्च: केरल में वाममोर्चा सत्तासीन। मार्क्सवादी नेता ई०के० नयनार के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया एएसएलवी ठीक ५२ सेकेंड के बाद बंगाल की खाड़ी में जा गिरा।

नये राष्ट्रपति: वेंकटरमण

२७ मार्च: केन्द्रीय विधि मंत्री अशोक सेन द्वारा प० बंगाल विधानसभा चुनाव में इंका की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा।

२८ मार्च: रामलीला मैदान में लोकदल-ब का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन।

३० मार्च: बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति की बोट क्लब पर आयोजित विशाल रैली में मुस्लिम नेताओं के उत्तेजक भाषण। गुजरात में रास्ता रोको आंदोलन में १० हजार किसान गिरफ्तार।

३१ मार्च: ज्योति बसु तीसरी बार प० बंगाल के मुख्यमंत्री बने। जी०टी० पैस इंडियन एयरलाइंस के नये महानिदेशक।

३ अप्रैल: प्रधानमंत्री द्वारा फेयरफैक्स मामले की जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की घोषणा।

४ अप्रैल: 'शेखर एक जीवनी' 'नदी के द्वीप,'

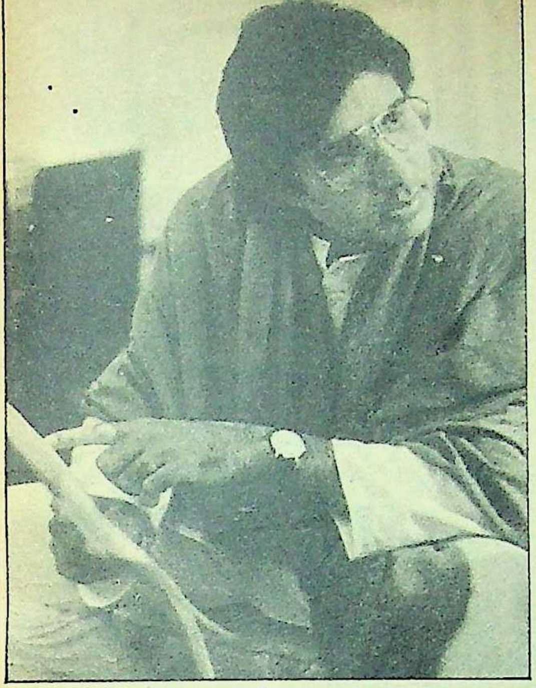

लोकसभा से इस्तीफा: अमिताभ बच्चन

'यायावर रहेगा याद' जैसे हिंदी ग्रंथों के बहुचर्चित कृतिकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का निधन।

१४ अप्रैल: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी हत्याकाण्ड के तीनों अभियुक्तों के फांसी की हत्या पर रोक लगाने का आदेश।

१७ अप्रैल: पंजाब में आतंकवादियों द्वारा १० निरीह लोगों की हत्या।

१९ अप्रैल: पंजाब में गत चौबीस घंटे में आतंकवादियों ने ११ लोगों को मौत के घाट उतारा।

२० अप्रैल: इंका सांसद हरद्वारीलाल का पार्टी व संसद सदस्यता से इस्तीफा।

२१ अप्रैल: नौसेना के वरिष्ठ कमांडर नवीन चोपड़ा द्वारा आत्महत्या।

२२ अप्रैल: तरनतारन (पंजाब) के एक ही परिवार के छह लोग आतंकवादियों के खूनी उन्माद के शिकार।

२७ अप्रैल: पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में ६ लोगों की बर्बर हत्या।

राजकपूर की सदाबहार 'बरसात' से हिंदी फिल्म जगत को अपनी सैकड़ों धुनों से मुग्ध करने वाली संगीतकार जोड़ी शंकर-जयकिशन की दूसरी शेष कड़ी-जयकिशन का निधन।

४ मई: केन्द्रीय कार्यान्वयन मंत्री ए०बी०ए०गनी खां चौधरी का इस्तीफा।

१० मई: पंजाब में मुठभेड़ों में ४ आतंकवादियों सहित १२ मरे।

११ मई: पंजाब में २९ सितंबर, ८५ को बनी बरनाला सरकार बर्खास्त और राष्ट्रपति शासन लागू। गोवा-देश का २५वां राज्य बना।

१२ मई: पंजाब में आतंकवादियों से सफलतापूर्वक लोहा ले रहे धुन, लगन, ड्यूटी के पक्के पुलिस महानिदेशक जूलियस रिबेरो का कार्यकाल एक साल बढ़ा।

१५ मई: स्वाधीनता आंदोलन की समूची शताब्दी की संघर्षपूर्ण आत्मबलिदानी गौरवगाथा को मूर्तमान करने वाले ९७ वर्षीय सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां इलाज के लिए बंबई के अस्पताल में दाखिल।

१६ मई: बोट क्लब पर कांग्रेस की विशाल रैली में प्रधानमंत्री द्वारा 'राजा जयचंदों', 'मीरजाफरों' जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने का आह्वान।

१९ मई: मेरठ के वीभत्स, बर्बर सांप्रदायिक दंगों में ५० मरे।

२० मई: इराडी आयोग की रिपोर्ट प्रसारित। पुरानी दिल्ली में हिंसक सांप्रदायिक घटनाओं के बाद सेना का फ्लैग मार्च।

२१ मई: उ०प्र० प्रशासन को अंगूठा दिखाता दंगाग्रस्त मेरठ, सेना के हवाले।

२२ मई: पूर्वी दिल्ली भी दंगों की चपेट में। नतीजतन ५ निर्दोषों की बलि चढ़ी।

२५ मई: मेरठ के दंगों की बेरोकटोक हिंसा में मृतकों की संख्या १५० तक पहुंची।

२७ मई: फेयरफैक्स से कोई अनुबंध न होने का दावा करने वाली सरकार द्वारा उससे 'अनुबंध समाप्त' करने का ऐलान।

२९ मई: पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चरण सिंह का निधन।

३० मई: औरंगाबाद जिले (बिहार) में 'क्रांति' की भ्रांति में ग्रस्त नक्सलियों ने ४१ लोगों की जान ली।

१ जून: राजकपूर की लगभग तमाम सफल फिल्मों के कथाकार, प्रख्यात फिल्म निर्देशक व स्तंभकार ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन। अजीत सिंह लोकदल-अ के नये अध्यक्ष।

२ जून: पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में ७ आतंकवादियों सहित १६ मारे गये।

४ जून: गृहयुद्ध की आग में जल रहे श्रीलंका में सेना से घिरे जाफना व अन्य तमिल इलाकों में आवश्यक जिंसों की सप्लाई के लिए भारतीय विमानों ने रसद गिरायी।

९ जून: रोहतास के जातीय दंगों में १२ की हत्या।

१० जून: दो सौ से अधिक हिंदी फिल्मों के बेजोड़ चरित्र अभिनेता और धार्मिक फिल्मों में नारद की भूमिका निभाने वाले जीवन का निधन।

AIFUCTO के आह्वान पर नये वेतनमानों
कालेजों के प्राध्यापक
18.8.87 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
8·1987 से

हड़ताली शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन

१३ जून: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, भाग-१ के बहल परिवार के एक बच्चे की वर्षगांठ पार्टी में आतंकवादियों ने गोलियां बरसाते हुए कई लोगों को मौत के घाट उतारा और फिर भागते हुए अलकनंदा और तुगलकाबाद में भी हत्याएं कीं। इन वारदातों में १४ निरीह लोग मारे गये।

१४ जून: पंजाब में आतंकवादियों ने १७ लोगों की हत्या की।

१५ जून: भाखड़ा नहर में यात्री बस गिरने से स्त्री-बच्चों सहित ८० लोग डूबे।

१६ जून: पंजाब के विभिन्न भागों में पुलिस मुठभेड़ों में ११ आतंकवादी मरे।

१८ जून: हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का लगभग सफाया तथा लोकदल-भाजपा गठबंधन विजयी।

२० जून: ३६ वर्षों तक पक्षियों का अध्ययन करने वाले और इस विषय पर आधा दर्जन से अधिक विश्वविख्यात पुस्तकों के रचयिता विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी सालिम अली का बंबई में निधन।

२२ जून: वी०आर० कृष्ण अय्यर (पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय) राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार।

२४ जून: जाफना के लिए राहत सामग्री लेकर भारतीय जहाज रवाना।

२६ जून: दिल्ली के हृदयस्थल कनाट प्लेस स्थित बहुमंजिली इमारत अंसल भवन में लगभग ६ घंटे तक लगी आग में ३ मरे।

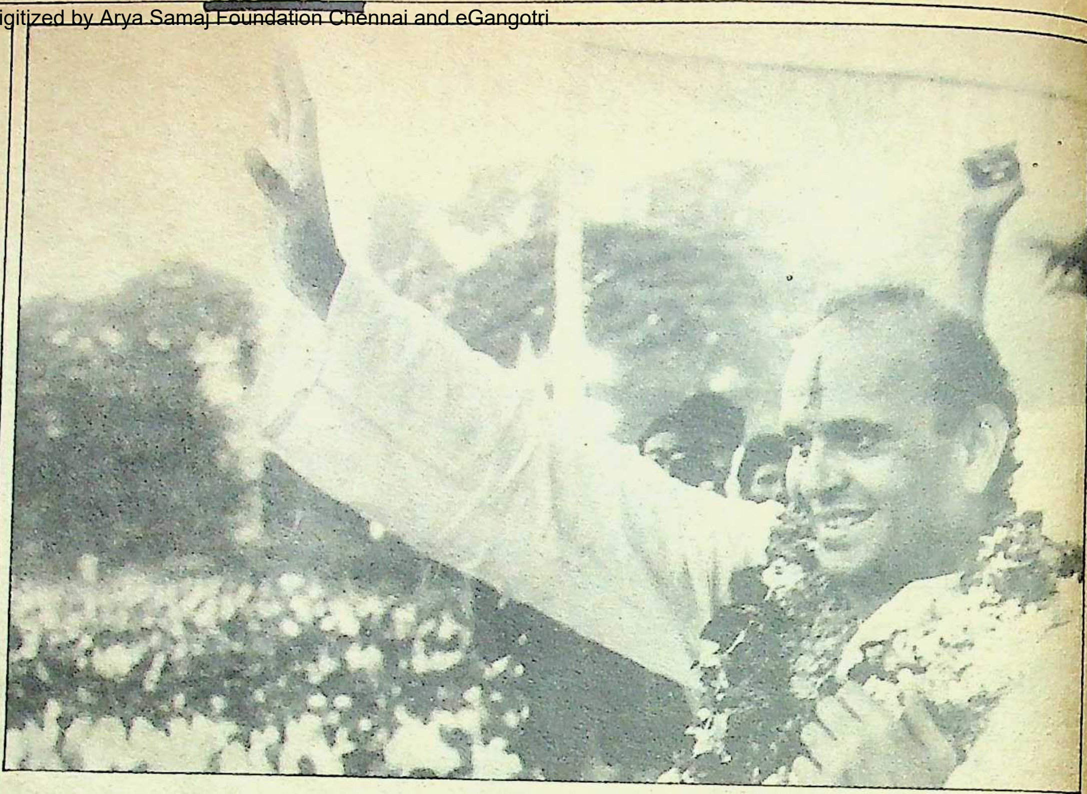

जनमोर्चा के गठन के बाद वी०पी० सिंह

हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देवीलाल

६ जुलाई: लाडलू में हरियाणा रोडवेज बस के ३८ यात्रियों की आतंकवादियों द्वारा दिनदहाड़े निर्मम हत्या।

७ जुलाई: हिसार-फतेहाबाद मार्ग पर आतंकवादियों द्वारा दो बसों के ३६ यात्रियों की बर्बरतापूर्वक हत्या।

६ जुलाई: दक्षिण एक्सप्रेस के दो डिब्बे गंदरगादी नदी (आंध्र) में गिरने से ५३ यात्रियों की मृत्यु।

१० जुलाई: पंजाब के पूर्व मंत्री सतनाम सिंह बाजवा सहित नौ की आतंकवादियों द्वारा हत्या।

१४ जुलाई: केन्द्रीय पर्यटन मंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद का इस्तीफा।

१५ जुलाई: वि०प्र० सिंह सहित अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल और आरिफ मोहम्मद खां कांग्रेस से निष्कासित।

१६ जुलाई: आर० वेंकटरमन भारत के ८वें राष्ट्रपति।

१७ जुलाई: बोफ़ोर्स सौदों में दलाली और स्विस बैंकों में खातों जैसे बहुचर्चित विवादों में फंसे सुपरस्टार सांसद अमिताभ बच्चन का लोकसभा से इस्तीफा।

१८ जुलाई: रक्षाराज्यमंत्री अरुण सिंह का इस्तीफा।

१९ जुलाई: आर्थिक अपराधियों के राजनीतिक रिश्तों को बेनकाब करने वाले राजीव मंत्रिमंडल के नबंर दो मंत्री वी०पी० सिंह कांग्रेस से निकाले गये। अजिताभ बच्चन की स्विस बैंक में जमा-जायदाद की जांच के आदेश।

२० जुलाई: उ०प्र० ऊर्जामंत्री सुनील शास्त्री का इस्तीफा।

२३ जुलाई: राष्ट्रपति जैल सिंह को राष्ट्रपति भवन में आतंकवादियों का आश्रयदाता बताने वाले के०के० तिवारी का मंत्री पद से इस्तीफा। मेरठ के पास ८ बस यात्रियों की हत्या।

२४ जुलाई: हिंसा का सहारा लेते हुए अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले सुवास घीसिंग की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भेंट।

२५ जुलाई: प्रधानमंत्री के विवादग्रस्त सचिव माखनलाल फोतेदार इस्पात-खान मंत्री नियुक्त।

१ अगस्त: बांबे डाइंग के चेयरमैन नसली वाडिया विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) के आरोप में गिरफ्तार।

७ अगस्त: पंजाब के जगदेव कलां में आतंकवादियों ने १२ लोगों को मारा।

९ अगस्त: भारत छोड़ो आंदोलन की ४५ वीं वर्षगांठ पर समारोह। अब्दुल गफ्फार खां को भारतरत्न की उपाधि।

१० अगस्त: प्रो० दर्शन सिंह रागी द्वारा राजनीति से संन्यास की घोषणा। देवीलाल द्वारा हरियाणा के किसानों-गरीबों के २२७.५१ करोड़ के कर्ज को माफ करने का ऐलान।

१५ अगस्त: स्वाधीनता की ४० वीं वर्षगांठ पर देशव्यापी पैमाने पर समारोह।

१६ अगस्त: भारतरत्न अब्दुल गफ्फार खां पेशावर रवाना।

१९ अगस्त: जालंधर में बूटा सिंह के ६ करीबी रिश्तेदारों की एक विवाहोपरांत जघन्य हत्या। मृतकों में नवविवाहिता भी।

२० अगस्त: जल संसाधन मंत्री बी० शंकरानंद का इस्तीफा।

२१ अगस्त: सत्ताधारी और विपक्षी दलों के एकमत से डा० शंकरदयाल शर्मा उपराष्ट्रपति निर्वाचित।

२२ अगस्त: उ०प्र० के परिवहन मंत्री संजय सिंह का इस्तीफा। 'फुटपाथ' फिल्म में दिलीप

पुस्तकालय
111155
गुरुकुल कांगड़ी विश्व. हरिद्वार

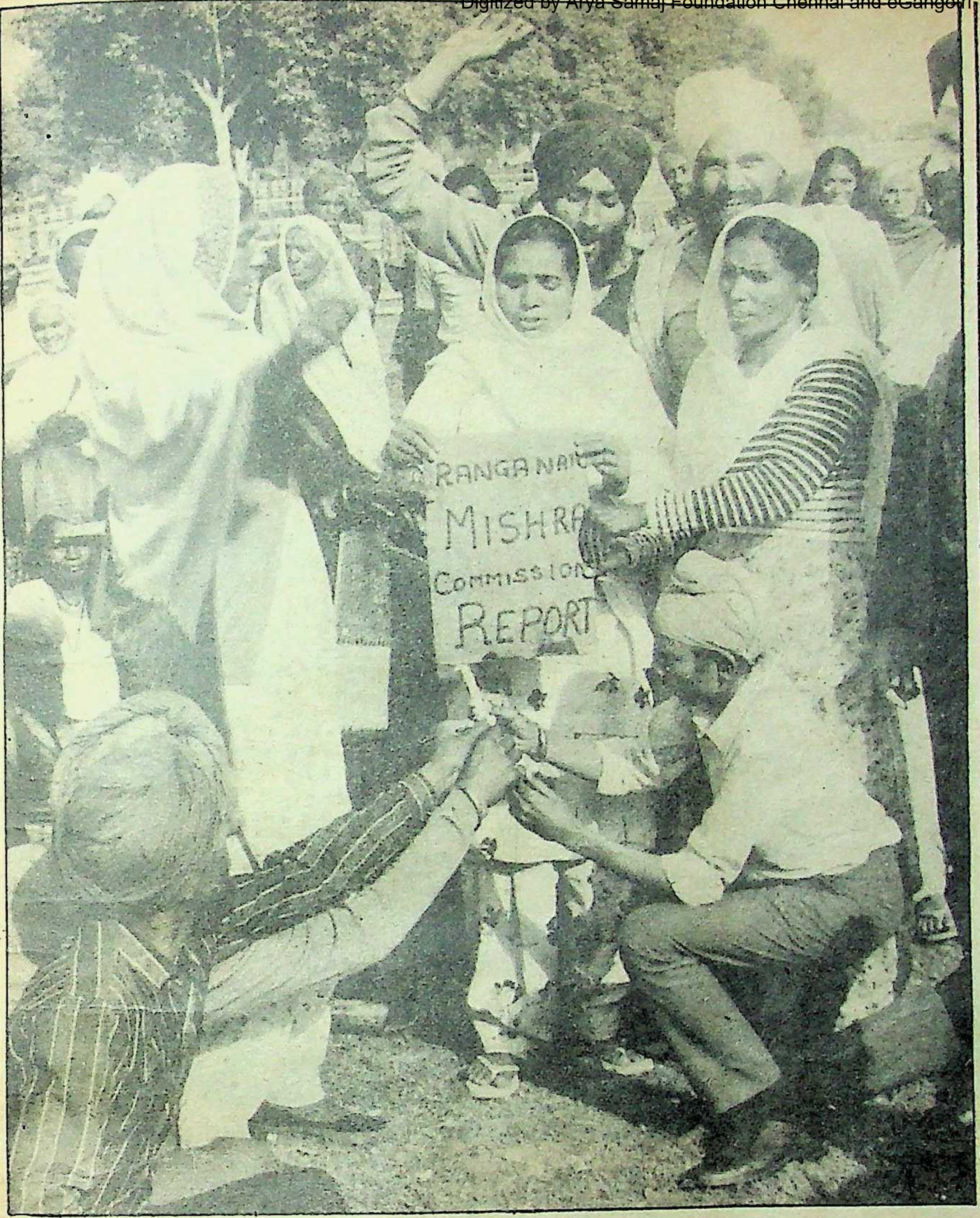

मिश्र आयोग की रपट जलाते सिख प्रदर्शनकारी

कुमार के साथ भूमिका करने वाले, बुद्धिजीवी, लेखक और 'सेमीनार' पत्रिका के बेबाक संपादक रमेश थापर का निधन।

२४ अगस्त: कांची मठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती अचानक गायब।

२५ अगस्त: सरस्वती कांची के नये शंकराचार्य।

२६ अगस्त: उड़िया के शीर्ष क्रांतिकारी कवि और ब्रिटिश शासन में (१९३०) में प्रतिबंधित 'अभियान' काव्य ग्रंथ के रचयिता सच्चिदानंद राउतराव को १९८६ का ज्ञानपीठ पुरस्कार।

२७ अगस्त: वी० शंकरानंद बोफोर्स जांच समिति के अध्यक्ष।

५ सितंबर: खाद्य आपूर्ति मंत्री गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा। दिवराला गांव में रूपकंवर सती।

५ सितंबर: कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी द्वारा पार्टी में पांच नये महासचिवों केदारनाथ सिंह, गुलाम नबी आजाद, आस्कर फर्नांडीस, नरेशचन्द्र चतुर्वेदी व राम रतन राम की नियुक्ति।

१० सितंबर: तथाकथित खालिस्तानी जन० बघेल सिंह मारा गया।

११ सितंबर: छायावाद की अन्यतम कवयित्री, नीहार, यामा, गीतपर्व, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा जैसे युगांतकारी काव्यसंकलनों व अतीत के चलचित्र, शृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं आदि गद्य कृतियों की सृजक ८० वर्षीया महादेवी वर्मा का निधन।

१२ सितंबर: उर्दू के मशहूर व्यंग्यकार और ३० वर्षों से अधिक चलने वाले कालम 'प्याज के छिलके' के रचयिता फिक्र तौंसवीं का निधन।

१४ सितंबर: बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष मोरबर्ग की रहस्यमय दिल्ली यात्रा और रक्षा मंत्रालय से लंबी वार्ताएं।

१७ सितंबर: तमिलनाडु के अरकाट में पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलीचालन से १३ मरे।

१८ सितंबर: मोरबर्ग की संसदीय जांच समिति के सामने गवाही। उ०प्र० के १६ लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल।

१९ सितंबर: सूखा बाढ़ राहत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ५५० करोड़ के नये कर।

२४ सितंबर: मोरबी शहर (गुजरात) में बम फटने से ९ मरे।

३० सितंबर: दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा

वोट क्लब पर भाजपाई रैली

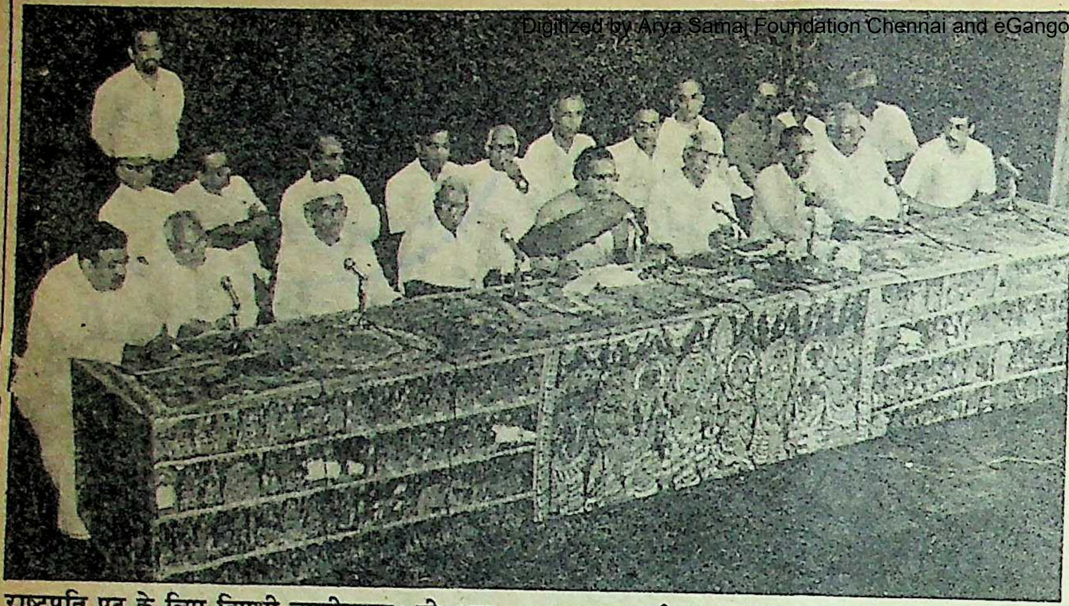

राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार: वी०आर० कृष्ण अय्यर की एक सभा

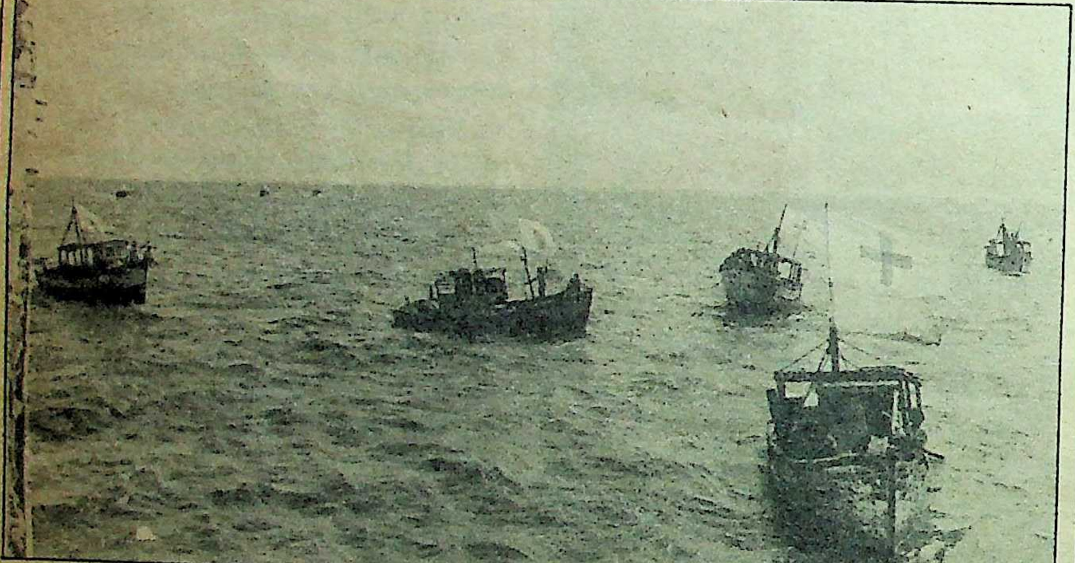

जाफना में राहत सामग्री ले जाती भारतीय नौकाएं

१३ अक्तूबर को किशोर कुमार नहीं रहे

रिलायंस क्रिकेट कप प्रतियोगिता का उद्घाटन।

२ अक्तूबर: वी०पी० सिंह द्वारा जनमोर्चा के गठन की घोषणा।

६ अक्तूबर: प्रख्यात क्रांतिकारी, स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार श्रीमती अरुणा आसफ अली को १९८६ का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता और सद्भाव पुरस्कार।

७ अक्तूबर: पांच सदस्यीय पंथिक कमेटी द्वारा राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद का गठन।

८ अक्तूबर: जनमोर्चा द्वारा १ करोड़ स्वयंसेवक भरती करने का फैसला।

१० अक्तूबर: जे०डी० नाडकर्णी नये नौसेना अध्यक्ष नियुक्त।

१२ अक्तूबर: बंबई (महाराष्ट्र) के सांसद गुरुदास कामत युवक कांग्रेस के नये अध्यक्ष।

१३ अक्तूबर: पांचवें दशक से हिंदी फिल्म जगत में पार्श्वगायक, अभिनेता, निर्देशक के रूप में झंडा गाड़ने वाले और हजारों लोकप्रिय फिल्मी गीतों के अमर गायक किशोर कुमार का निधन।

१४ अक्तूबर: दिल्ली के एक्सप्रेस समूह के अखबारों में अनिश्चितकालीन हड़ताल।

१५ अक्तूबर: भटिंडा (पंजाब) के समीप यात्री बस में आग से ४० मरे।

१६ अक्तूबर: गुरुद्वारा शिरोमणि कमेटी दो हिस्सों में बंटी। संयुक्त अकाली दल ने गुरुचरण सिंह तोहड़ा व अकाली दल (लोंगोवाल) ने हरचरण सिंह हुडियारा को अध्यक्ष चुना।

१८ अक्तूबर: तीन मुख्यग्रंथी—ज्ञानी कश्मीर सिंह, ज्ञानी सविंदर सिंह और ज्ञानी जसवंत सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंदी।

रा०स्व०से० संघ और भाजपा सहित समान विचारों वाले संगठनों की नागपुर में पांच दिवसीय संयुक्त बैठक समाप्त।

२० अक्तूबर: आतंकवादियों द्वारा दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क में काली पूजा के एक पंडाल में घुसकर तथा उस क्षेत्र के आसपास की गयी खूनी वारदातों में १२ लोग मरे। स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रस्तावित सरबत खालसा रोकने के लिए पुलिस का प्रवेश और व्यापक

उत्तराखण्ड क्रान्तिदल
उत्तराखण्ड क्रान्तिदल जिन्दाबाद

उत्तराखण्ड की मांग को लेकर बोट क्लब पर रैली

जलती
नारी की
पुकार
बंद करो ये
अत्याचार!

सामाजिक विकृति का प्रतीक, सती-प्रथा का विरोध

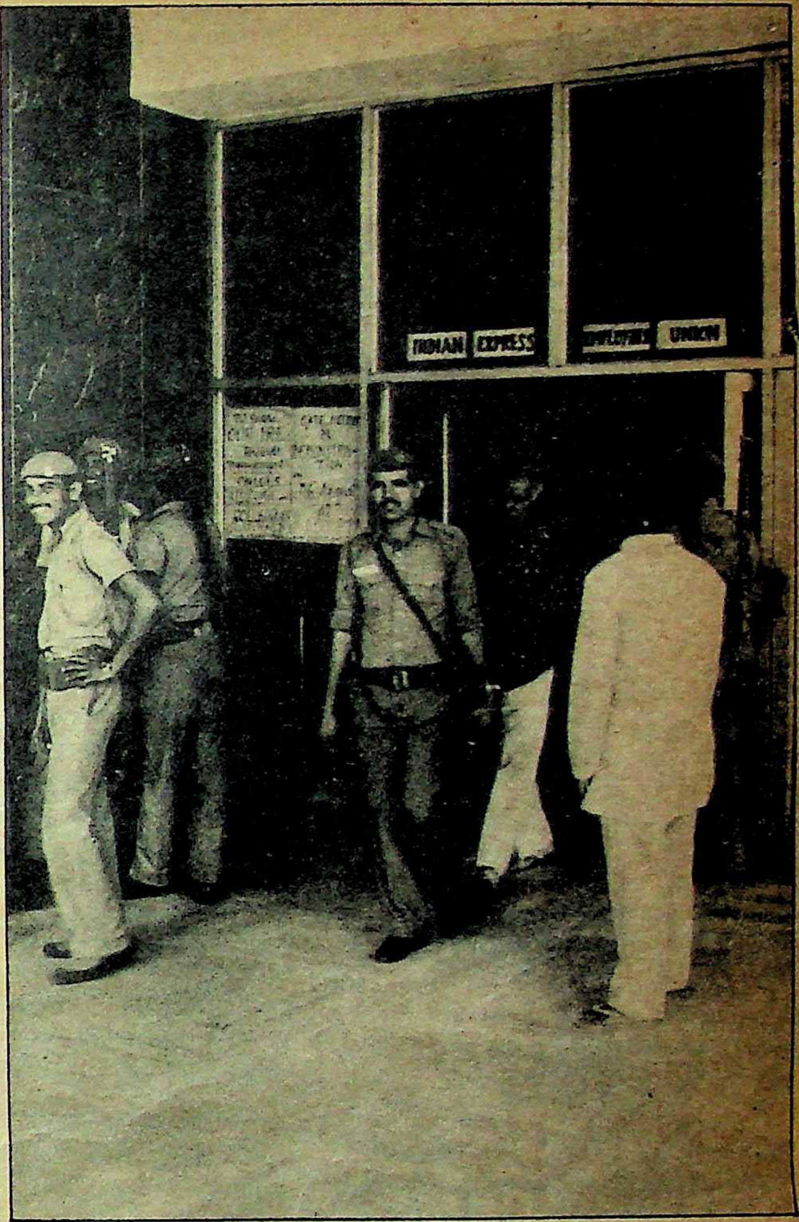

इंडियन एक्सप्रेस पर छापा

धरपकड़।

२४ अक्तूबर: सुरक्षा बलों का आतंकवादियों-असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर (अमृतसर) में प्रवेश। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सी० सुब्रह्मण्यम को अणुव्रत पुरस्कार की घोषणा।

२७ अक्तूबर: देश के महान क्रिकेट खिलाड़ी और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता ७७ वर्षीय विजय मर्चेंट का निधन। आतंकवादियों द्वारा पंजाब में एक महिला, एक सरपंच व एक ग्रंथी सहित १३ की हत्या। केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पेश।

११ नवंबर: पंजाब में आतंकवादियों द्वारा कम्युनिस्ट नेता दर्विदर सिंह सहित ७ की हत्या।

१४ नवंबर: केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भवन निर्माण कार्यवाहियों को अवैध करार देते हुए भवन के किरायेदारों को सरकार के पास किराया जमा कराने का आदेश।

१७ नवंबर: अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार प्रो० दर्शन सिंह रागी का इस्तीफा।

१६ नवंबर: हिंदी के प्रख्यात नाटककार, उपन्यासकार और कथाकार डा० लक्ष्मीनारायण लाल का निधन।

२१ नवंबर: भारत में एक वर्ष चलने वाले सोवियत महोत्सव के राजधानी में रंगारंग भव्य उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के प्रधानमंत्री (रिझकोव-राजीव) शामिल।

२२ नवंबर: होकिशो सेमा के नेतृत्व में नागालैंड में २० सदस्यीय मंत्रिमंडल द्वारा शपथ।

२४ नवंबर: उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर बोट क्लब पर रैली।

२६ नवंबर: अजमेर से दिल्ली जा रही ट्रेन में आग लगने से २२ मरे। भागलपुर जिले के रानी-दियारा घाट के पास अपराधकर्मियों द्वारा नाव पर सवार १२ मछुआरों की हत्या।

२ दिसंबर: संयुक्त अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल एक साल की नजरबंदी के बाद जबलपुर केन्द्रीय जेल से रिहा। इंडियन एक्सप्रेस समूह दिल्ली के समाचारपत्रों का-४८ दिनों की हड़ताल के बाद-पुनः प्रकाशन।

४ दिसंबर: दिल्ली में न्याय यात्रा पर आनेवाले लगभग ५०० अकाली कार्यकर्ता गिरफ्तार।

६ दिसंबर: फेयरफैक्स कांड की जांच के लिए नियुक्त ठक्कर-नटराज आयोग द्वारा पेश रिपोर्ट में सारा दोष वि०प्र० सिंह के माथे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था।

चार वामपंथी दलों-भाकपा, माकपा, आरएसपी व फारवर्ड ब्लाक-द्वारा राजीव गांधी से इस्तीफा देने, नये चुनाव कराने, महंगाई, बेकारी खतम करने, पृथकतावादी-सांप्रदायिक ताकतों से सख्ती बरतने आदि की मांगों पर राजधानी में विशाल रैली।

—प्रस्तुति: त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव करायेंगे

—भवानी सेन गुप्त

फ्रांसीसी लोगों के लिए 'आदर्श राष्ट्रपति' कैसा हो, यह जानने के लिए हाल में पेरिस में एक जनमत संग्रह कराया गया था। इससे ज़ो इमेज (छवि) उभरी, वह यह थी कि राष्ट्रपति ४९ वर्ष का, पांच फुट ११ इंच लंबा, विवाहित और तीन बच्चों का बाप, दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान, ईमानदार और लोगों से जुड़ा होना चाहिए। फ्रांसीसी लोगों के लिए उनके प्रधानमंत्री में तेजस्विता, ईमानदारी और दूसरों के प्रति लगाव, ये तीन गुण जरूर होने चाहिए।

अभी तक भारत में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की है कि लोग किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं। ४० वर्ष पुराने भारतीय गणराज्य को एक प्रधानमंत्री में शासक के अलावा अन्य गुणों की भी जरूरत है। आजादी के बाद अधिकांश भारतीयों ने भी सिर्फ एक शासक भर की तलाश नहीं की है। इंदिरा गांधी भी मुट्ठी भर कांग्रेसियों की पसंद थीं, न कि सब लोगों की। राजीव तो सिर्फ अपनी मां की पसंद थे और वह रिकार्ड मत से चुनाव भी इसीलिए जीते, क्योंकि दो अंगरक्षकों ने उनकी मां की हत्या कर दी थी। इस महीने वह अपने शासन काल के चौथे वर्ष में कदम रख रहे हैं। क्या १९८८ उनके पहले कार्यकाल का अंतिम वर्ष होगा? क्या वह मध्यावधि चुनाव कराकर फिर से जनमत हासिल करना चाहेंगे? चार नवंबर को उन्होंने इस बात का खंडन किया कि वह मध्यावधि चुनाव कराने की सोच रहे हैं। थोड़ी कुटिल मुस्कराहट के साथ उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने काफी एकता दिखायी है। वह उन्हें एक होने के लिए कुछ और समय देना चाहते हैं। पर इस बात के पक्के संकेत मिल रहे हैं कि अगले साल मार्च-अप्रैल या फिर सितंबर-अक्तूबर में राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव करायेंगे। अधिक संभावना मार्च-अप्रैल की ही है।

नागालैंड में कांग्रेस की जीत न तो उनके लिए कोई 'टानिक' बनने जा रही है और न ही यह 'क्षेत्रीयतावाद' की पराजय है, जैसा कि कुछ रिपोर्टरों का दावा है। इससे भी बड़ी बात है पार्टी द्वारा देश भर में जनसंपर्क का जबर्दस्त अभियान शुरू करना। पंजाब और उ०प्र० पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा संकेत इंका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ता मेलजोल है। अगर अपने तीन साल के शासनकाल में राजीव गांधी ने कोई बात सबसे अधिक स्पष्ट की है, तो यही कि घरेलू नीति में वह किसी एक विचारधारा को पकड़कर चलना नहीं चाहते। चूंकि वह प्रधानमंत्री बने रहने से आनंदित हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि चुनावी राजनीति में वह ऐसे किसी भी हथकंडे को आजमा सकते हैं जो उन्हें लोकसभा में स्पष्ट बहुमत दिला सके।

पर एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री के रूप में चौथा साल शुरू करने के पूर्व ही राजीव गांधी की वह इमेज धूमिल हो चुकी है, जिसने टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री खरीदने वाले आठ करोड़ भारतवासियों के मन में ढेर सारी उम्मीदें जगायी थीं। अब वह 'विपदा के मारे एक तेजतर्रार' नौजवान नहीं रहे, जिसे ७८ करोड़ लोगों के देश की बागडोर सौंप दी जाये। उनके चेहरे पर आज भी चमक है, पर इसमें सत्ता की चकाचौंध भी शामिल हो गयी है। उनका गंजा होता जा रहा सिर आसानी से नजर आ जाता है। उनकी तोंद भी थोड़ी निकल आयी है जिसे वह किसी गोपनीय सैनिक जानकारी की तरह छिपाये रहते हैं। 'मिस्टर क्लीन' वाली उनकी इमेज अब नहीं रही। उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए हैं और शायद कभी होंगे भी नहीं, पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया जाये, तो अधिकांश लोग उन्हें ईमानदार घोषित करने में हिचकेंगे। प्रतिष्ठा एक बार जाने के बाद शायद ही फिर बन पाती है। इसी कारण ओथेलो का कैसियो रोता है, "मैंने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी। मैंने अपने जीवन का अनश्वर हिस्सा तो गंवा ही दिया...," लेकिन उन्हें कोई 'मिस्टर डर्टी' भी नहीं कहेगा। हाल में वह 'श्रीमान असफल' जरूर हो गये हैं और इस मामले में दुनिया के किसी भी जिंदा या मुर्दा प्रधानमंत्री की इतनी भद नहीं हुई थी।

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, जो अभी गरमाने तो लगा है, पर उबला नहीं है, उनकी स्थिति क्या है? यह बात लंदन की पत्रिका 'द इकानामिस्ट' में छपे एक सर्वेक्षण से बहुत अच्छी तरह सामने आती है। पत्रिका में कहा गया है, "राजीव गांधी जब सत्ता में आये थे तब चार राज्यों में 'विरोधी' सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, तीन बड़े विद्रोह और कुछ छोटे विद्रोह जारी थे। दो साल बाद चार राज्यों में उन्हीं लोगों ने चुनाव जीतकर सरकारें बना ली हैं, जिन्हें उनकी मां देशद्रोही कहती थीं। तीन विद्रोहों में से एक दब चुका है। दूसरा भी करीब-करीब दबाया जा चुका है और पंजाब अभी पहले की तरह ही उग्र रूप धारण किये हुए है। कई छोटे विद्रोह जारी हैं। श्री गांधी के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व नीति का अभी तक तो यही नतीजा सामने आया है।"

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभालते वक्त देश और पड़ोस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कही भी थी। पर यह बात जोड़-घटाने की खिचड़ी से आगे नहीं बढ़ पायी है। इसकी एक अहम वजह यह है कि राजीव गांधी ने अभी वह हैसियत हासिल नहीं की है जो संक्रांति काल से गुजरते लोकतंत्र में किसी नेता को हासिल होनी चाहिए। एक दल के वर्चस्व से कई दलों के वर्चस्व वाले लोकतंत्र की ओर जाने के लिए ऐसा होना जरूरी है। उनका तरीका अभी भी विमान को किसी तरह सुरक्षित उतार लेने वाले पाइलट जैसा ही है। राजनीति के प्रति उनका दून स्कूल वाला रवैया असफल हो गया है। उनकी तेज और स्पष्ट अंतर्दृष्टि अब कहने लगी है कि राजनीति सिर्फ हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई से नहीं चल सकती और भारत जैसे विकासशील देश में कंप्यूटर उपयोगी तो है, किंतु बहुत सीमित रूप में। बहुत ही अराजनीतिक बुद्धि, जिसमें समस्या को

ठीक करना ही घुसता है, वाले राजीव अभी भी राजनीतिक प्रक्रिया से अनजान आदमी हैं और अकसर यह मान बैठते हैं कि वह तो इन सब झमेलों से ऊपर रहने के लिए पैदा हुए हैं। जिस राजनीतिक ढांचे के साथ प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, उसका हर पुरजा बिखर गया है। अरुण नेहरू विरोधी खेमे में पहुंच गये हैं। अरुण सिंह राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गये हैं। अर्जुन सिंह की असलियत सबके सामने आ चुकी है। जिन राजकुमारों और राजाओं पर उन्होंने विरोधी तकनीक और पूंजी के बल पर देश को आधुनिक बनाने की आस लगा रखी थी, उनको ही यह भरोसा नहीं है कि मंत्रिमंडल का अगले फेरबदल या मध्यावधि चुनाव वह झेल भी पायेंगे या नहीं। २१वीं सदी की तलाश करते-करते प्रधानमंत्री '१७वीं सदी' के कांग्रेसी नेताओं को ढूंढ़ लाये हैं। संसद में कृष्ण चंद्र पंत ने किसी भी अन्य नेता की तुलना में रक्षा सौदों के विवाद में उनकी बेहतर रक्षा की। इस विवाद से बचाव का कुछ काम रक्षा उपकरणों के संबंध में खुलेपन की नीति और संसदीय अखाड़े के पुराने अनुभव ने ही किया। कभी गलती न करने का विश्वास या एक झूठ से बचने में झूठ का जाल रच कर फंसने की रीगन जैसी नीति की इसमें चलने वाली नहीं थी। उन्हें कमलापति त्रिपाठी को पुनर्स्थापित करना पड़ा। संगठन के अंदरूनी चुनाव कराने के लिए उमाशंकर दीक्षित के पास दौड़ना पड़ा। उन्हें शायद जल्दी ही इस बात का भी पता लग जायेगा कि सांगठनिक चुनाव कराने के बावजूद वह पार्टी के रंगढंग को नहीं बदल सकते। या तो चुनाव हो ही नहीं पायेंगे या हुए भी तो उन्हीं लोगों की सत्ता पर मुहर लगेगी जो आज और उनकी मां के आखिरी दस वर्षों में भी पार्टी के सर्वेसर्वा थे।

प्रधानमंत्री हठपूर्वक इससे इनकार करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से कांग्रेस का वर्चस्व अब टूट रहा है। १९८३ से ही पार्टी ने चुनाव हारना शुरू कर दिया था। तब पूरा दक्षिण उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद से उत्तर का कुछ हिस्सा और पूर्व का अधिकांश भाग भी निकल चुका है। वैसे अभी भी २४ में १३ राज्य उसके प्रभाव में हैं, पर उसका प्रभाव क्षेत्र हिंदी भाषी राज्यों और गुजरात तथा महाराष्ट्र तक में सिमट गया है। विपक्ष के छितराये होने की स्थिति से प्रधानमंत्री इसी सीमा तक खुश हो सकते हैं कि अगले चुनावों में उनकी पार्टी को कामचलाऊ बहुमत मिल जाये। पर १९८९-९० में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसके हाथ से कुछ और राज्य निकल जायेंगे, जिससे १९९० के दशक में राजनीतिक गणित गैर कांग्रेसी दलों के पक्ष में हो जायेगी। सिर्फ शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व वाली नीति के बल पर ही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना राज नहीं बचा पायेगी। बहुदलीय और बहुकोणीय राजनीतिक प्रक्रिया में तनाव शैथिल्य भी चाहिए। अधिकारों और संसाधनों का विकेंद्रीकरण केंद्र से राज्यों को तथा वहां से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयीं स्थानीय निकायों को किया जाना चाहिए, लेकिन इंका [illegible] में स्थानीय निकाय काम ही नहीं कर रहे हैं।

इसमें सिर्फ राजीव गांधी का कसूर नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के निर्जीव पदार्थ के बड़े पिंड में कांग्रेस-इ एक ऐसा निष्क्रिय पिंड है, जिसमें कोई भी रसायन हरकत पैदा नहीं कर सकता। उनकी मां ने पार्टी को सत्ता में बने रहने का हथियार बना लिया और मुख्यमंत्रियों को अपना टट्टू। राजीव गांधी के पास आज एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो चुनाव जीत सके। वह उन लोगों को भी नहीं हटा सके जो उन्हें गाली देते हैं, जो अपनी और पार्टी की जड़ खोदने वाली करतूतें करके अगले चुनाव में मिट्टी पलीद कराने का पूरा बंदोबस्त करते जा रहे हैं। आज भी उनकी पार्टी उसी स्थिति में है जैसी तीन वर्ष पहले। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद कहा था, "हम (कांग्रेसी) कोई अनुशासन, कोई नियम और आम नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं मानते, सामाजिक चेतना का प्रदर्शन नहीं करते और जनता की भलाई के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाते। यहां भ्रष्टाचार को सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं किया जाता उसे नेतृत्व का गुण माना जाता है।" उसके बाद के तीन वर्षों में पार्टी की और दुर्गति ही हुई है। इसमें जानकी बल्लभ पटनायकों, वीर बहादुरों, हरिदेव जोशियों और बिंदेश्वरी दुबेओं का जोर बढ़ा है। ये लोग हिंदी भाषी इलाके में दरारों वाले सत्ता के किलों को कैसे संभालेंगे?

चौथे वर्ष में प्रधानमंत्री खुद को चार फंदों में फंसा पाते हैं। वह पार्टी, नौकरशाही, अपनी इमेज बनाने वालों और कामचलाऊपन की उलझन में फंस गये हैं। नौकरशाही के साथ तो उनका कुछ अजीब सा रिश्ता चल रहा है। पार्टी के फंदे के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। इंका इतने गुटों में बंट चुकी है कि उसे ठीक करना मुश्किल है। अब अगर इसमें कोई गतिशीलता बची है, तो वह है आपसी लड़ाई-झगड़ों और उठापटक की। जिन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, वे पार्टी के खिलाफ हो जायेंगे और कांग्रेसी लोग ही कांग्रेसी उम्मीदवारों की हार का एक मुख्य कारण बनेंगे। नौकरशाही में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो प्रधानमंत्री द्वारा की गयीं पहल पर भी ना कर देते हैं। इसके बावजूद वे ही प्रधानमंत्री को ज्यादा भाते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उनको दुत्कारते भी हैं, क्योंकि वे यथास्थिति से आगे बढ़ना नहीं चाहते। उनकी इमेज बनाने वालों ने बड़ी गलती कर दी। वे उन्हें आठ या १२ करोड़ मध्यमवर्गीय लोगों को आधुनिक बनाने वाला बताकर ही पेश करते रहे, जबकि उनकी मां की इमेज हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की 'अम्मा' वाली थी। भारत के गरीब ही किसी को प्रधानमंत्री बनाते-हटाते हैं, किसी की सरकार बनाते या गिराते हैं। राजीव इस चीज को अब थोड़ा समझने लगे हैं, पर अभी भी उनके और गरीबों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई है। वह उनकी भाषा नहीं बोलते। गरीब खुद को उनसे जुड़ा नहीं पाते और उनके आधुनिकीकरण के अभियान ने इन लोगों के जीवन को कहीं से भी प्रभावित नहीं किया है। और इसी कारण हथियार खरीद के घोटालों और 'अमीर विरोधी' विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटाने के बाद इन हंगामों को दबाने के लिए पिछले अप्रैल में इंका आलाकमान ने जो लंबा प्रस्ताव स्वीकार किया था उसे आज 'पागलपन का दस्तावेज' कहा जाता है। प्रस्ताव में साम्राज्यवाद विरोधी जो जुमलेबाज़ी की गयी या गरीबों के नाम पर आंसू बहाये गये हैं, उन्हें भी कोई याद नहीं करता। अंत में, आखिरी फंदा फैसला लेने की प्रक्रिया का कामचलाऊपन है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार चल रही है। यही लगता है कि मैनेजर जैसे-तैसे काम निकालते जा रहे हैं। किसी को भी पता नहीं है कि किसके जिम्मे क्या है? हां, हर आदमी को इतना पता जरूर है कि प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर पर हर चीज की जिम्मेवारी है।

दिल्ली और पंजाब में भले ही स्टेनगनों की आवाज गूंज रही हो, पर राजीव गांधी की अंतरराष्ट्रीय छवि पर कोई आंच नहीं आयी है। लोग एक बार फिर उनकी ओर उम्मीद से देखने लगे हैं। अगर उन्हें जनमानस के मन में अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखवाना है, तो इन चार फंदों को तोड़ना होगा। और अगर उन्हें १९८८ का मध्यावधि चुनाव जीतना है, तब तो यह बहुत जरूरी है। ■

१९८७ का आकलन

नये साल को विरासत में क्या मिलेगा ?

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही जोर-शोर से जिस उदार अर्थनीति का ढिंढोरा पीटा गया था, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकी ?

प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब अपने शासनकाल का एक वर्ष पूरा करने जा रहे थे, तब (१९८५ के आखिरी दिनों में) अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने कहा था, "भारत में राजीव गांधी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की अपनी नीति से चमत्कार पैदा कर रहे हैं। वह भारतीय आम जनता, व्यापारियों और भारत में दुनिया भर से पूंजी लगाने के इच्छुक लोगों के मन में एक नया विश्वास जगा रहे हैं।" उन दिनों अखबारों में, पत्रिकाओं में तथा बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और बड़े अधिकारियों के बीच राजीव की जय-जयकार हो रही थी। ऐसा माहौल बन रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था उड़ान भरनेवाली है, जिससे अमीर और अमीर होंगे, तो गरीबों को भी रोटी-कपड़ा-मकान नसीब हो सकेगा। टेलीविजन सवा पांच लाख गांवों और ३००० शहरों तक पहुंच जायेगा। कंप्यूटर बहुत कुशलता और तेजी से काम निपटा दिया करेंगे और सामान का उत्पादन तथा विभिन्न जनसेवाओं की वृद्धि की रफ्तार १९७४ के बाद के दस-ग्यारह वर्षों की तुलना में और तेज हो जायेगी।

उम्मीदों पर पानी: जब अखबार-पत्रिकाओं और रेडियो-टी॰वी॰ ने नये प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों का गुणगान शुरू कर दिया, तो आम आदमी भी अपने नसीब सुधरने के सपने देखने लगा। मध्यम वर्ग जिसे कभी चैन की रोटी नसीब नहीं होती, वह भी शेयर बाजार-संस्कृति से परिचित हो गया। अपना पैसा बैंक में पड़े रहने देने की जगह, उससे कमाई करने का यह बढ़िया तरीका था। सस्ते शेयर खरीद लो और दाम चढ़ने पर बेच दो। इस दौर में जिस भी कंपनी के नये शेयर आये उनकी कई गुना अधिक बुकिंग हुई। ऐसे निवेशकों को अगर अपने आवेदन के आधे शेयर भी मिल जाते थे, तो वे अपने को भाग्यशाली समझते थे। इस दौर में कुछ ने तो सच में कमाई कर ली, पर कुछ मारे गये। बड़े पैमाने पर फरेब चालू हो गये। नयी कंपनियों ने इतने नाटक रचे कि निवेशक उनके शेयरों को भी पाकर निहाल हो जाते थे। कुछ नयी कंपनियों ने तो अपनी पूरी फैक्टरी लगाये बिना भी, जितने के शेयर जारी किये, उससे अधिक पैसे जुटा लिये। कुछ तो ये सारा धन लेकर चंपत भी हो गये और निवेशक कमाने के चक्कर में अपनी गांठ की कौड़ी भी गंवा बैठे।

उदारवादी नीति का पतन: राजीव गांधी

आज शेयर बाजार की हालत खस्ता है। यह पिछले साल (१९८६) के सितंबर-अक्तूबर वाली स्थिति में पहुंच गया है। नामी-गिरामी कंपनियों को भी नये शेयर जारी करके वांछित रकम जुटा पाना बेहद मुश्किल हो गया है। शेयर बाजार से निवेशकों का भरोसा उठ गया है। अब तो वहां सिर्फ खूब पैसेवाले (जो घाटा सह सकते हैं) और शेयर बाजार के मंजे हुए अखाड़िये ही रह गये हैं। दूसरे शब्दों में, आम लोगों को शेयर खरीदने-बेचने का जो बुखार चढ़ा था, वह उतर चुका है।

प्रमुख शहरों की सड़कों पर देखिए कि प्रति सौ कारों में मारुति, प्रीमियर—१८८, कांटेसा और विदेशी कारों की संख्या कितनी है? यह तय है कि इस गिनती से आप निश्चिंत हो जायेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गयी है और जब आप रंगीन टेलीविजन, नयी रसोईघर के लिए उपयोगी विभिन्न यंत्रों और इलेक्ट्रानिक प्रेस बटन वगैरह की बिक्री के आंकड़ों को देखेंगे, तो इस धारणा को और बल मिलेगा। पिछले दो वर्षों के अंदर खुले वीडियो क्लब, वीडियो टेप या घरेलू उपकरण बेचनेवाली दुकानों की संख्या जानकर आप जरूर थोड़ा निश्चिंत हो जायेंगे कि व्यापार कई गुना बढ़ गया है और पश्चिम में जो तकनीक या उपकरण आ गये थे, उन्हें खरीदने और इसका आनंद उठाने के लिए ढेर सारे लोगों के पास पैसा आ गया है और आज भी अर्थव्यवस्था और व्यापार की स्थिति पर टिप्पणी करनेवाले कुछ लोग अपने मन में यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि अगर भारत उनके बताये रास्ते पर चला, तो वह भी अमरीका हो जायेगा।

लेकिन ये आंकड़े और तथ्य दूसरी ही कहानी कहते हैं। १९८७ में देश की जनसंख्या ८० करोड़ हो रही है और इसका अर्थ हुआ १९८५ की तुलना में ३.८ करोड़ अधिक लोगों की वृद्धि। सूखे के बाद गरीबी रेखा के नीचे रहनेवालों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत भी बढ़ेगा। 'इकानामिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो' का अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक भारत में सबसे अधिक निरक्षर होंगे।

बेरोजगारी: तीन करोड़ से अधिक लोगों ने तो अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज करा रखे हैं। पिछले तीन वर्षों में जितना पूंजी-निवेश हुआ है, उससे रोजगार के बहुत कम अवसर बन पाये हैं। दूसरी ओर हजारों छोटे उद्योग बंद पड़े हैं या बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं, परिणाम यह हुआ है कि इन उद्योगों में काम करनेवाले कम-से-कम दस

लाख मजदूर बेकार हो गये हैं।

राजीव शासनकाल के पहले डेढ़ वर्षों में बहुत उत्साह जगानेवाले बड़े उद्योगों की स्थिति क्या है? इकानामिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो द्वारा हाल में दी गयी रिपोर्ट इसकी झलक दे सकती है। रासायनिक खाद उद्योग ४० लाख टन से अधिक अनबिके माल के भंडार से परेशान है और हर कोई जानता है कि रबी की इस फसल या खरीफ की अगली फसल में खादों की अधिक खपत संभव नहीं है। कपड़ा उद्योग की हालत तो सबसे अधिक खराब है। इस क्षेत्र के बड़े उद्योगों के २.१० लाख करघे, पावरलूम क्षेत्र के १० लाख करघे और हथकरघे क्षेत्र की ७० लाख इकाइयां बंद पड़ी हैं। इन मिलों में १६००० करघे हैं। अन्य १०० मिलें भी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रही हैं। उनकी करघा-क्षमता २५००० से अधिक है। इंजीनियरी उद्योग में भारी मशीनों या इस्पात से लेकर साइकिल तक आती हैं। इंजीनियरी उद्योग संघ के हाल के सर्वेक्षण में ढेर सारी कंपनियों के प्रवक्ताओं ने कहा कि वे इस साल या मार्च के तुरंत बाद भी कोई बहुत अच्छी संभावना नहीं देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे लोग मानते हैं कि इंजीनियरी उद्योगों में हुए भारी निवेश का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

फिर, किन उद्योगों की हालत अच्छी है? आटो-मोबाइल? घरेलू उपकरण समेत इलेक्ट्रानिक्स के सामानों? सीमेंट या खाद्य पदार्थ या शराब?—इन उद्योगों की कुछ चीजें आज निश्चित रूप से अधिक बिक रही हैं। पर ऐसे उद्योगों में आपस में भारी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। टेलीविजन बनानेवाली कंपनियों की संख्या पहले ही काफी हो चुकी है, लेकिन अब बड़ी और नामी कंपनियों का धंधा ही अच्छा चल रहा है। श्वेत-श्याम और रंगीन टेलीविजन की मांग बढ़ने की उम्मीदें लगाये ढेर सारी कंपनियां बाजार में आ गयी हैं और इनमें काफी पूंजी लगी है। अधिकांश नयी कंपनियों ने नामी विदेशी कंपनियों से किसी-न-किसी तरह का गठबंधन कर रखा है। भारी आपसी होड़ के कारण उनके विज्ञापन का खर्च तो बढ़ गया है, पर उस हिसाब से बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

सीमेंट उद्योग: सीमेंट उद्योग के भी बहुत बुरे हाल हैं। यहां भी नयी फैक्टरी लगाने या उत्पादन-क्षमता बढ़ाने पर काफी पूंजी लगती है। सरकार द्वारा कई बार सीमेंट के मूल्य में बढ़ोतरी करने के बावजूद उस उद्योग से और रियायतों की मांग बंद नहीं हुई है। उनका तर्क है कि जिस कीमत पर वे माल बेचना चाहते हैं, उस पर पर्याप्त माल नहीं बिकता। इस कारण मुनाफे की दर घट गयी है। लेकिन यह स्थिति बहुत विचित्र है। देश में जिस तरह से आवास की समस्या है, उस हिसाब से सीमेंट की बिक्री तेजी से होनी चाहिए। शुरू में यह सोचा गया था कि उत्पादन की तुलना में मांग अधिक रहेगी, सो सरकार ने सीमेंट तैयार करने के लिए पर्याप्त क्षमता बना ली। आज देश को जितने सीमेंट की जरूरत हो, उतनी तैयार हो सकती है, पर अब मांग न रहने से यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता भर उत्पादन नहीं कर सकता। अगर अधिक मुनाफे के लिए कीमत बढ़ा दी गयी, तो मांग और घट जायेगी।

आटो-मोबाइल में कार, ट्रक या अन्य भारी और मध्यम वाहन, दो और तीन पहिया गाड़ियां शामिल हैं। भारी और हलके व्यावसायिक वाहनों के मामले में मांग की कमी तो पिछले कुछ समय से है और स्थिति में दो वर्ष में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। मध्यम दर्जे के वाहनों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन कारों की हालत खस्ता है। मारुति को छोड़कर किसी अन्य कार के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी होती, बल्कि ये आपको किश्तों में भी मिल सकती हैं या फिर आपको सरकार या बैंकों से कार खरीदने के लिए कर्ज भी मिल सकता है। इससे साफ है कि इस उद्योग के पास भी वर्तमान उत्पादन से अधिक की क्षमता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि इस उद्योग में लगी पूंजी के हिसाब से लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है।

आइये, कृषि का हाल देखें! सरकार द्वारा लंबे समय तक काफी पूंजी लगाने के बाद आज यह स्थिति बनी है कि मुश्किल-वाले वर्ष में भी हम (दालों को छोड़कर) जरूरी पैदावार कर सकते हैं जिससे सबका पेट भर सके। वैसे, इस साल तो भारी सूखे के कारण कुल पैदावार में दस फीसदी कमी होने की उम्मीद है। पर खेती के मामले में भी दलहन और तिलहन की भारी कमी पड़ती जा रही है। दरअसल, इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास कुछ किया नहीं गया है। इससे बड़ी बात यह है कि अधिकांश गरीब लोग खेती पर आश्रित हैं और थोड़ी भी गड़बड़ हो, तो उनके लिए भुखमरी की शुरुआत हो जाती है। खेती की पैदावार में जब भी ठीकठाक बढ़ोतरी नहीं होती, गरीबों की संख्या बढ़ जाती है। इस साल तो सूखा है, सो गरीबों की संख्या बढ़ेगी ही। अगले साल भी हालात सुधर जायेंगे, ऐसा नहीं लगता। सूखे की काली छाया अगले दो वर्षों तक परेशानी पैदा करेगी।

प्रधानमंत्री की उदारवादी नीति
चल नहीं पायी है। उन्होंने उन लोगों के मन में
जरूर उम्मीदें जगायी हैं जो
नयी तकनीक का लाभ प्राप्त करने के लिए
पैसा खर्च कर सकते हैं।
या जो व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम-से-कम कराके
मुनाफा कमाने की पर्याप्त आजादी चाहते हैं।
आयकरदाताओं को उन्होंने कुछ राहतें दीं,
पर आगे करों में और छूट की
संभावनाओं को समाप्त करके उन्होंने इन्हें भी
बेमजा कर दिया है।

जब कृषिजन्य कच्चे माल उद्योगों को कम मात्रा में मिलेंगे, तो उन्हें आयात पर अधिक आश्रित होना पड़ेगा, जिसका अर्थ होगा और अधिक विदेशी मुद्रा का खर्च। कपास, मूंगफली, सरसों, अलसी और अन्य तिलहनों के उत्पादन में कमी का असर तेल और कपड़ा मिलों पर बहुत बुरा होगा। इसके अलावा उद्योगों से तैयार होनेवाले माल की काफी मात्रा में खपत तो ग्रामीण इलाकों में होती है। यहां के लोगों की आमदनी की मुख्य स्रोत खेती ही है। उपज कम होने से उनकी आमदनी कम होगी और औद्योगिक उत्पादनों की मांग भी गिरेगी। अर्थात रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, कपड़ा, जूते, दियासलाई, चीनी, गुड़ तथा भवन निर्माण में लगने वाले सीमेंट और इस्पात जैसी चीजों की खपत भी कम हो जायेगी। आज भी कृषि क्षेत्र ही औद्योगिक उत्पादनों का सबसे बड़ा हिस्सा खपाता है और सूखे का असर उद्योगों पर क्या होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में आंख पर पट्टी बांधकर आशावादी बना बैठा आदमी ही कह सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है या फिर प्रधानमंत्री का अंधभक्त ही उन आंकड़ों-तथ्यों को झुठला सकता है। पर एक बात स्पष्ट है। प्रधानमंत्री की उदारवादी नीति चल नहीं पायी है। उन्होंने उन लोगों के मन में जरूर उम्मीदें जगायी हैं जो नयी तकनीक का लाभ प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं या जो व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम-से-कम कराके मुनाफा कमाने की पर्याप्त आजादी चाहते हैं। आयकरदाताओं को उन्होंने कुछ राहतें दीं, पर आगे करों में और छूट की संभावनाओं को समाप्त करके उन्होंने इन्हें भी बेमजा कर दिया है।

बहरहाल देश के अधिकांश लोगों की उम्मीदें राजीव-शासन के पहले साल में ही मुरझा गयी थीं। और कोई आश्चर्य नहीं कि इसी वजह से सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र के इसी अनिश्चित माहौल के कारण लोग शेयर बाजार में पूंजी लगाने से हिचकिचा रहे हैं।

—मालिनी चक्रवर्ती

मूंछें नीलाम, सिर्फ एक रुपए में !

समाज का हर मूल्य बदल रहा है, ऐसी स्थिति में मूंछों की क्या बिसात ! एक जमाना था, जब 'मूंछ का सवाल' था, लेकिन अब मूंछों का सवाल ही नहीं उठता। कभी मूंछें पुरुषत्व की प्रतीक थीं, लेकिन आज पुरुषत्व की परिभाषा बदल चुकी है। यदि कोई कह दे कि तुम्हारी मूंछें उखाड़ लूंगा, तो समझिए पूरी-की-पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गयी और जूती-पैजार पर लोग उतर जाते थे। इसीलिए प्रतिवाद में लोग यह भी कहते हुए सुने जाते हैं कि जाओ, जाओ देखा है, तुम हमारी मूंछ का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते। शायद इसीलिए माना जाता था कि 'बिना मूंछ का मरद और बिना पूंछ का बरद' बराबर होता है। कभी मूंछों का बड़ा मान था। राणा प्रताप ने मूंछों के चलते ही घास की रोटियां खायीं। हिटलर की मूंछें इतनी मशहूर थीं कि लोग उसी की तरह मूंछें रखने लगे थे। फिल्मों में उसकी मूंछों की नकल होने लगी थी। आज समय बदल गया है, फिर भी सुनते हैं कि मिलिटरी सेवाओं में मूंछ रखने तक का एलाउंस मिलता है और सबसे बड़ी मूंछें रख कर गिनीज बुक में नाम लिखवाने वाले लोग भी हैं। मूंछों का चाहे उतना महत्व न रहा हो, लेकिन यदि कोई अपनी मूंछें बेच दे, तो आश्चर्य तो होगा ही। ऐसा आश्चर्य मुजफ्फरनगर से करीब २५ किलोमीटर दूर शाहपुर कस्बे में हुआ है, जहां एक व्यक्ति ने केवल एक रुपए में अपनी मूंछें बेच दीं। उसने अपनी मूंछ विवशता के कारण बेची या लोभवश, पता नहीं चल सका, क्योंकि उसे बेचने के बाद वह तुरंत बाजार से चंपत हो गया। यह तो ज्ञात नहीं हो सका कि वह कहां गुम हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी मूंछें खरीदीं, उसके हाथ में रखी मूंछों को देखने वालों का मजमा लग गया।

वाह री मधुमक्खियों !

यों तो मधुमक्खियां मधु बिखेरने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हीं मधुमक्खियों के छत्ते को कोई छेड़ने का प्रयास करे, तो कहते हैं, मधुमक्खियां बदला लेने में भी अपना सानी नहीं रखतीं। हकीमी में तो शहद का इतना बड़ा उपयोग है कि प्रायः हर दवा के साथ उसको मिलाकर खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं यदि मधु और घी मिलाकर कोई चख ले, तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसी हैं मधुमक्खियां और उनका माहात्म्य, लेकिन वे रेल को चलने से भी रोक सकती हैं, इस पर जरा विश्वास नहीं होता। यदि टिड्डियों के लिए यह बात कही जाती, तो सहसा विश्वास हो जाता, लेकिन मधुमक्खियां इस अदावत पर उतर आयेंगी, कोई सोच नहीं सकता। यह घटना बंगलादेश की है। उत्तरी बंगलादेश में हजारों मधुमक्खियों ने एक यात्री रेलगाड़ी को तकरीबन दो घंटे तक चलने नहीं दिया। ढाका से लगभग ८० किलोमीटर दूर जब ट्रेन ईंधन के लिए रुकी, तो हजारों मधुमक्खियां इंजन में घुस गयीं, मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी रोक कर उतरना पड़ा और यात्रियों की मदद लेनी पड़ी। यात्रियों द्वारा लगभग दो घंटों तक घास जलाकर उसकी लपटें मधुमक्खियों को दिखानी पड़ीं, तब कहीं जाकर मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा। उनके भागने के बाद ही ड्राइवर इंजन के डिब्बे में घुस पाया और ट्रेन चल सकी। एक तो बंगलादेश वैसे ही राजनीतिक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, इस पर ये मधुमक्खियां !

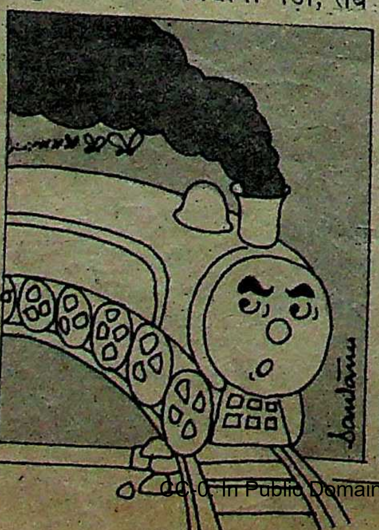

गधे की किस्मत !

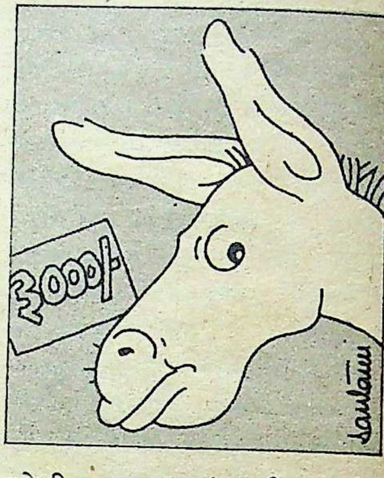

गधा जिसे प्यार से 'बैसाखनंदन' कहा जाता है, वाकई गधा ही होता है—आकृति की दृष्टि से भी और स्वभाव की दृष्टि से भी। गधा एक ऐसा चौपाया है जो सभी चौपायों में निपट भोंदू माना जाता है, लेकिन गधा ऐसा उपयोगी जीव है कि अगर किसी से स्वार्थ सिद्ध करना है, तो हम अपने आपको 'गधा' कहने में संकोच नहीं करते-यह समय का तकाजा है। कभी-कभी तो हम गधे को बाप तक कह देते हैं। यह दूसरी बात है कि कृष्ण चंदर जैसे स्वनामधन्य साहित्यकार ने 'एक गधे की आत्मकथा', लिखकर 'गधे' शब्द को महिमामंडित कर दिया है, लेकिन लब्बोलुबाब यही है कि हम उसे निकृष्ट एवं बेवकूफ ही समझते हैं। सोचते हैं कि इसका जन्म तो मात्र लादी ढोने के लिए ही हुआ है, लेकिन कभी-कभी ईश्वर गधे पर भी अपनी दयार्द्र बूंदें न्यौछावर कर देता है। हुआ यह कि उत्तरी बिहार के सोनपुर में लगने वाले बिहार पशु मेले में उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के कारण मेले का मवेशी-बाजार अत्यंत फीका रहा और मेलहरियों की संख्या भी बहुत कम रही। एक पखवाड़े तक चलनेवाले इस मेले में खरीद-फरोख्त की शुरुआत काफी मंद रही, लेकिन गधों की किस्मत खुली रही। अच्छी नस्ल के गधों की कीमत एक हजार से तीन हजार रुपए तक रही। आज तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी कीमत खुद उनकी नजरों में एक पैसे की नहीं है, दूसरे की नजरों की तो बात ही और है ! ऐसे में गधे को उनसे सौभाग्यशाली तो कहना ही पड़ेगा, चाहे बिकने के बाद वह लादी ढोये या ईंट-पत्थर !

परलोक से वापसी

कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज निश्चित है, तो वह है मृत्यु। मृत्यु से कोई भी लड़ नहीं सकता, लड़कर जीत नहीं सकता और जिसकी मृत्यु आ जाये, उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। एक बार जिसे डाक्टरों ने मृत करार दिया हो, वह यदि पुनः जीवित हो जाये, तो अजूबा तो होगा ही। ऐसी ही चमत्कारी घटना हुई फागो के ग्यारह वर्षीय एल्बरो गार्जी के साथ जो एक जमी हुई नदी में लगभग ४५ मिनट तक फंसा रहा। किसी प्रकार उसे वहां से निकालकर सेंट ल्यूक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरी जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद वह एकाएक उठ बैठा और अपने परिजनों तथा मां-बाप को पूर्ववत पहचानने लगा। एल्बरो का इलाज करनेवाले चिकित्सक विलियम नारबर्ग ने यद्यपि उसकी हालत नाजुक बतायी है, लेकिन डा० विलियम सहित सभी अन्य चिकित्सक अचम्भित हैं कि डाक्टरों द्वारा मृत घोषित किया जाने वाला एल्बरो जीवित कैसे है ?

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

हर महफ़िल में रंग जमा दे!
McDowell's
DIPLOMAT
DIPLOMAT
McDowell's
DIPLOMAT
COLOGNE

नये ऐतिहासिक तथ्य

क्या मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी ?

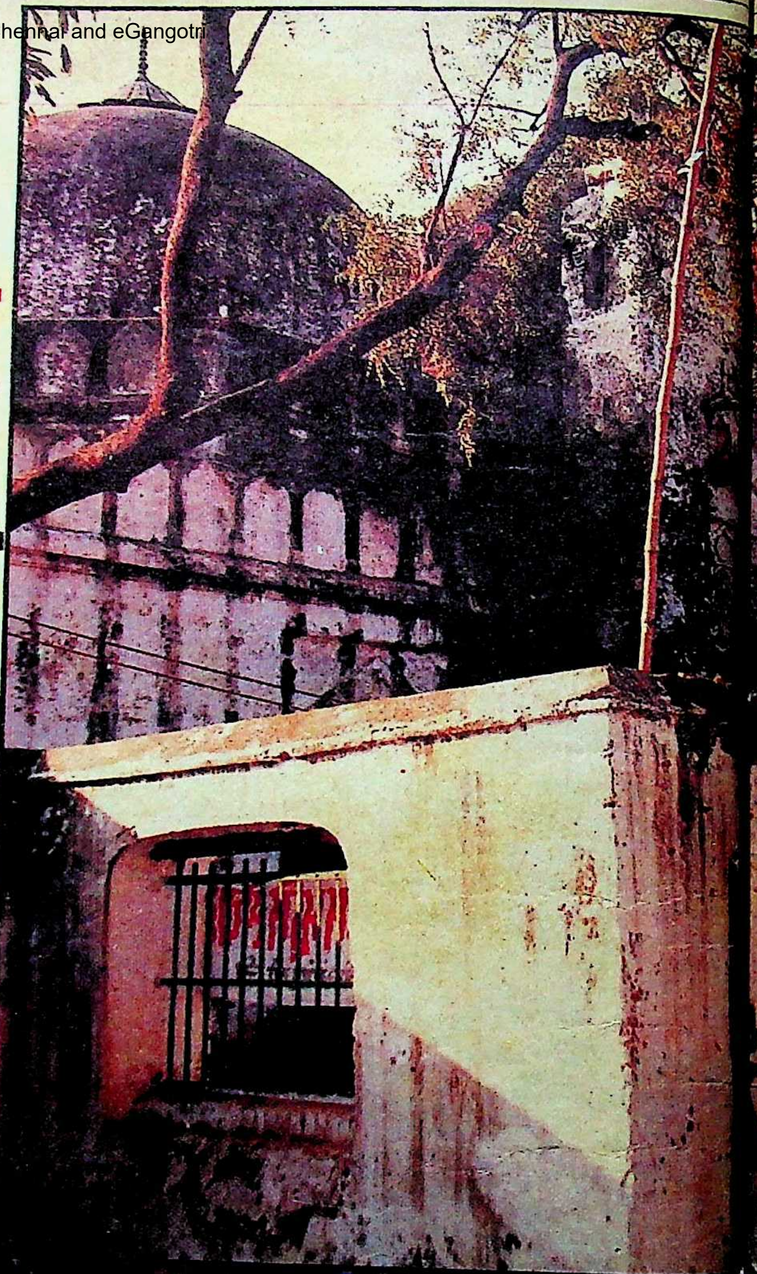

राम जन्मभूमि के पक्षधर

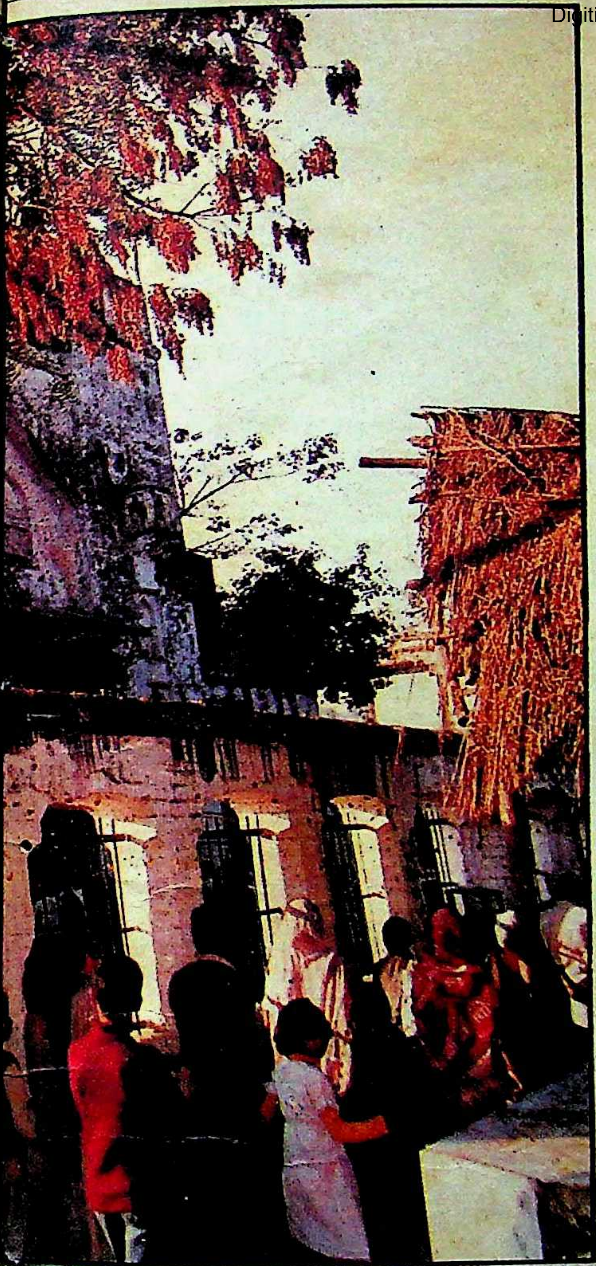

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की विषाक्त जड़े, इस व्यापक धारणा से जन्मी हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने १५२८ में तोड़ा था और उसकी जगह अपने नाम पर मस्जिद का निर्माण किया था जो अब भी स्थित है। एक तटस्थ शोधार्थी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा विश्वास करने के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है कि बाबरी मस्जिद उस मंदिर को तोड़ कर बनी है जो राम के जन्म के स्थान पर बना था ? क्या यह बात सप्रमाण कही जा सकती है कि उस मस्जिद को स्वयं बाबर ने बनवाया था या उसके हुकुम से बनी थी ? और अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर नहीं था, तो क्या था ? यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए फैसला देने का अधिकार तो अदालत के पास ही है। लेकिन हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के प्रवक्ता सुशीलश्रीवास्तवद्वारा उपर्युक्त प्रश्नों के संदर्भ में की गयी ऐतिहासिक शोध को ज्यों-का-त्यों प्रबुद्ध पाठकों के सामने रख रहे हैं।

इस शोध को प्रकाशित करने का उद्देश्य तर्क, इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला की रोशनी में इस विवाद पर ठंडे दिमाग से सोचने के लिए सुधी पाठकों के सामने तथ्य प्रस्तुत करना है, ताकि देश पर छाये धार्मिक उन्माद के कुहासे से मुक्ति पाने का कोई रास्ता मिल सके। यह जरूरी नहीं कि इस शोध से 'माया' सहमत हो, इसलिए इस शोध से जो नये प्रश्न खड़े हुए हैं और जो प्रश्न अनुत्तरित रह गये हैं, उनको अलग से दिया जा रहा है, ताकि सभी पक्ष जागरूक पाठकों के सामने आ सकें। →

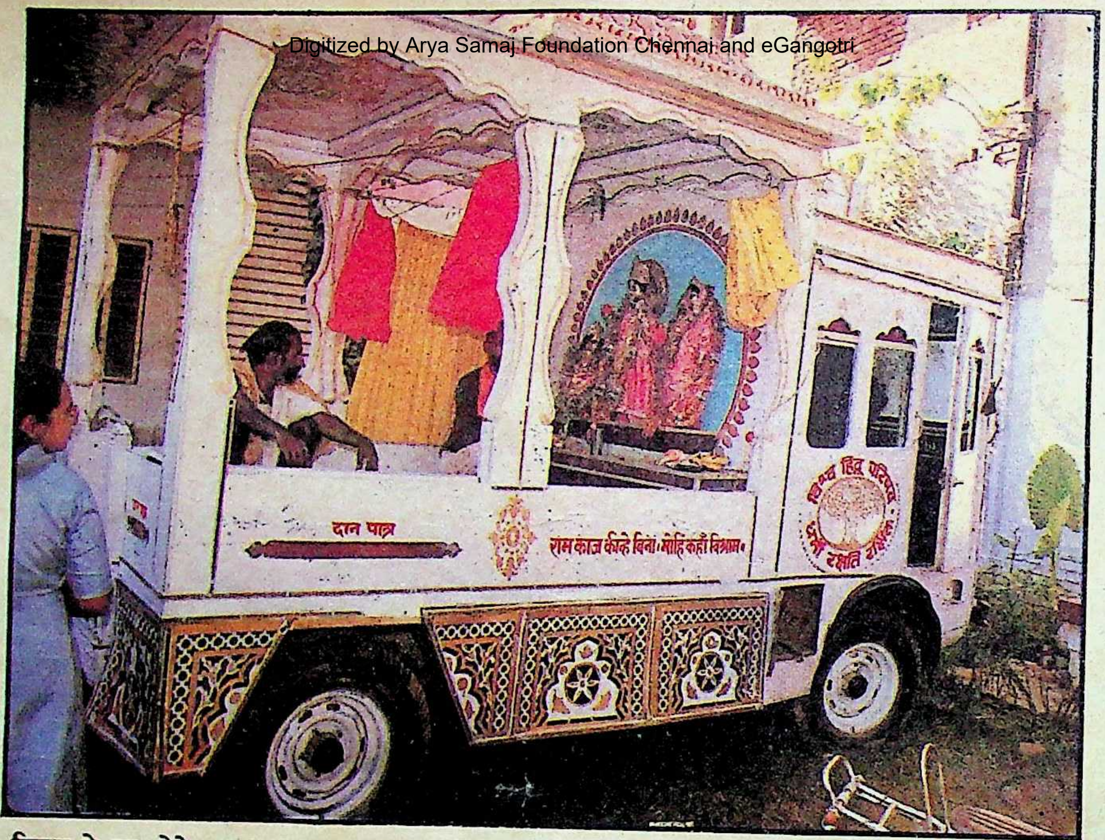

विवाद के उग्र होने का एक कारण: रामजानकी रथ

छाया: मनमोहन शर्मा

ऐसा विश्वास है कि राम जन्मभूमि मंदिर वहां स्थित था, जहां बाबरी मस्जिद बनी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास का आधार- मुख्यतया मिथ, लोकगीत एवं लोकश्रुतियां हैं।

चूंकि माहात्म्य में कुछ स्थलों की निश्चित दूरी नहीं दी गयी है और दूसरे संदर्भों में भी विसंगतियां हैं, ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि मस्जिद ठीक जन्म स्थल पर है?

राम जन्म भूमि मंदिर ?

ऐसा विश्वास है कि राम जन्मभूमि मंदिर वहां स्थित था, जहां बाबरी मस्जिद बनी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास का आधार मुख्यतया मिथ, लोकगीत एवं लोकश्रुतियां हैं। वैसे ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से संबंधित मंदिर उसी स्थान पर स्थित था। हिंदू धर्मग्रथों में भी ऐसे किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि इस विश्वास का मुख्य आधार वाल्मीकि की 'रामायण' है। इस ग्रंथ में अयोध्या नगर को राम का जन्म स्थान बताया गया है।इस संबंध में ए० कनिंघम ने अपनी 'आर्कियोलोजिकल रिपोर्ट,' १८६२-६३ में लिखा है:

"रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी की स्थापना संपूर्ण मानव जाति के पूर्वज 'मनु' ने की थी। राम-के पिता दशरथ के समय इसकी बुर्जियों और द्वारों के साथ उसकी किलेबंदी की गयी और इसके चारों ओर गहरी खाई खोदी गयी। इस निर्माण का अब कोई अवशेष नहीं है। ऐसा संभव भी नहीं—और यदि राम की अयोध्या का कोई अंश बच भी गया होगा, तो ऐसा माना जाता है कि वह ईसा पूर्व १४२६ के महायुद्ध में वृहदबाला की मृत्यु के बाद नष्ट कर दिया गया होगा। इसके बाद विक्रमादित्य के समय तक यह नगर निर्जन रहा। जनश्रुति के अनुसार यह विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध शकारि राजकुमार थे। लेकिन इस समय के हिंदू सारे विक्रमादित्यों के कार्यों को इसी एक विक्रमादित्य से जोड़ते हैं, लेकिन यह बात बिलकुल निराधार है। यद्यपि ह्वेनसांग की राय है कि इस नाम (विक्रमादित्य) का एक शक्तिशाली राजकुमार पड़ोस के श्रावस्ती नगर पर शासन करता था। यह कनिष्क के ठीक सौ साल बाद या ७८ ई० के आस-पास की बात है।(अब यह स्थापित हो गया है कि कनिष्क का समय ७८ ई० था, इसलिए यह समय १७८ ई० होना चाहिए—स०)। यह समय शालिवाहन द्वारा प्रवर्तित शक संवत् का प्रारंभिक वर्ष था। उक्त विक्रमादित्य को बौद्धों के प्रति कठोर माना जाता था, लेकिन वह अवश्य पक्के ब्राह्मणवादी रहे होंगे। अतः मैं मानता हूं कि उन्होंने ही अयोध्या का पुनर्निर्माण और राम के इतिहास से सम्बद्ध सभी पावन-स्थलों का जीर्णोद्धार किया होगा। जनश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचे, तो उन्हें यह उजाड़ और जंगलों से ढका मिला। लेकिन पुराने रिकार्डों से पता चलता है कि सरयू के लक्ष्मण घाट से माप-जोख करके वह राम के इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को खोज निकालने में सफल हुए। बताया जाता है कि उन्होंने राम और उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तथा वानर देवता हनुमान से संबंधित विभिन्न पूज्य स्थानों पर ३६० मंदिरों का निर्माण किया।" यों तो अनेक इतिवृत्त-लेखकों और यात्रियों के लेखों में भी अयोध्या का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें किसी में भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। 'मिरात-ए-मसूदी' में भी इस मंदिर का जिक्र नहीं है। न इब्न बतूता के 'रहेला' में और न ही 'बाबरनामा' में इसका उल्लेख है। हां 'आईने अकबरी' (अबुल फजल लिखित अकबर के संस्मरण) में अवश्य कहा गया है कि अयोध्या नगरी

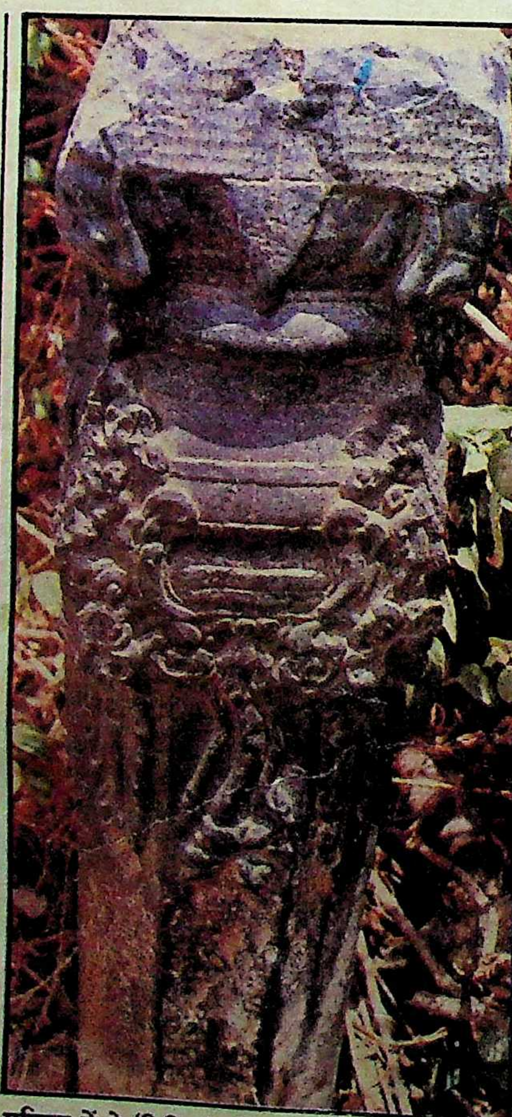

मस्जिद में ये 'निषिद्ध' खंभे कहां से आये?

छाया: राजेंद्र कुमार

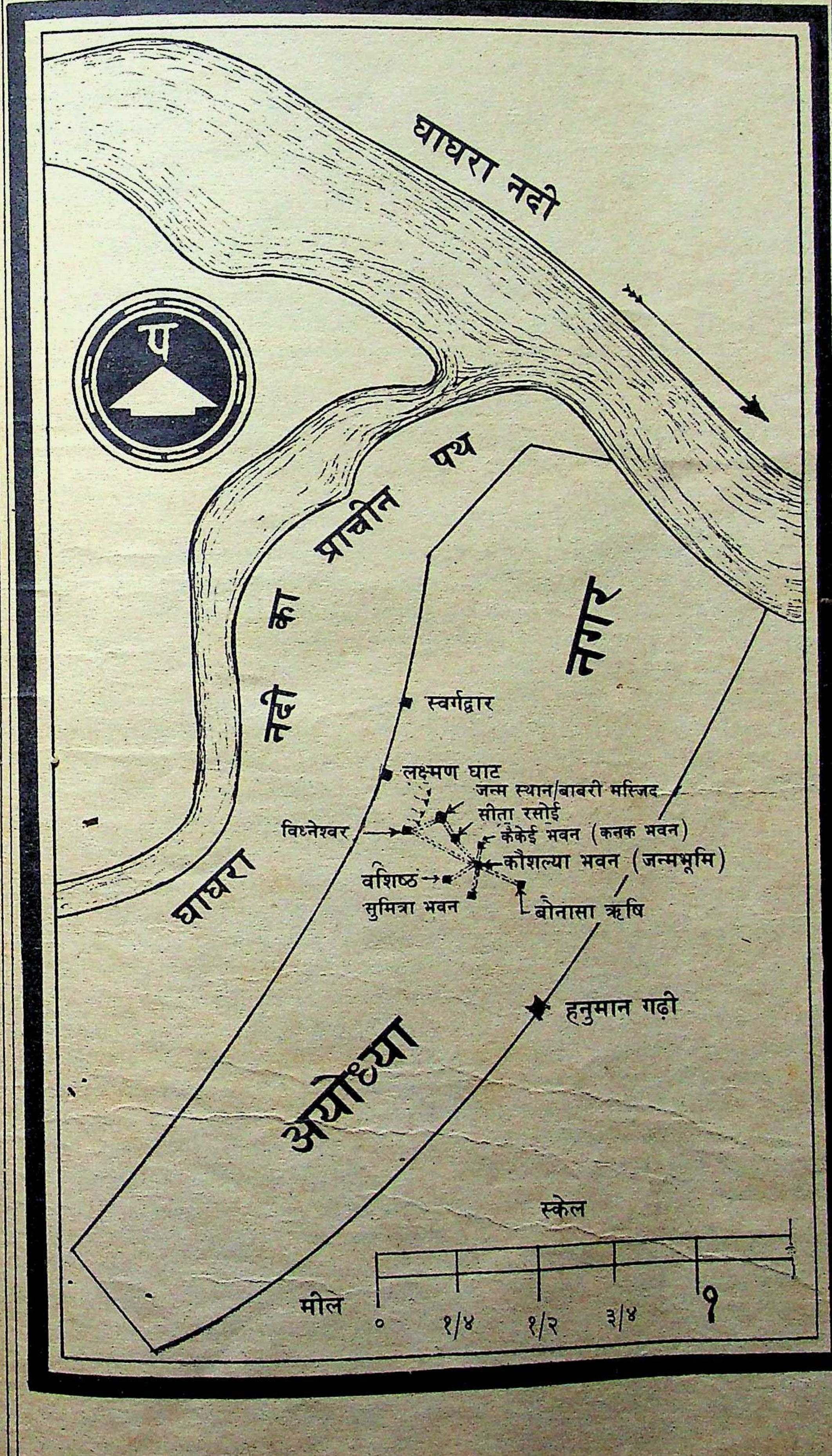
घाघरा नदी
प
नदी का प्राचीन पथ
नगर
स्वर्गद्वार
लक्ष्मण घाट
जन्म स्थान/बाबरी मस्जिद
सीता रसोई
विघ्नेश्वर
कैकेई भवन (कनक भवन)
कौशल्या भवन (जन्मभूमि)
वशिष्ठ
सुमित्रा भवन
बोनासा ऋषि
हनुमान गढ़ी
घाघरा
अयोध्या
स्केल
मील
०
१/४
१/२
३/४
1

को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है।

अतः यह तो सर्वमान्य है कि संपूर्ण अयोध्या राम जन्मभूमि थी और इसका भी उल्लेख है कि यहां अनेक मंदिर थे। लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि यहां श्री राम जन्मभूमि नामक मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी।

तो फिर यह विश्वास कब, कैसे और क्यों प्रचलित हुआ कि यहां 'श्री राम जन्मभूमि' नामक मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश शासन के दौरान 'मिथकों' को काफी लोकप्रियता हासिल हुई। सबसे पहले १८५० ई० के बाद इस बात का उल्लेख ब्रिटिश अधिकारियों ने किया कि हिंदुओं के पूजा-स्थलों को मुगल शासकों ने अपवित्र किया। इसकी पुष्टि मोहम्मद फैज बख्श की कृति 'तारीखे फराहबख्श' (१८१६ ई० तक के फैजाबाद के संबंध में) से होती है। इसमें १७२० ई० और १८१६ ई० के बीच फैजाबाद में हुई घटनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा है, लेकिन इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई हिंदू पूजा-स्थल रहा है और उसको लेकर कोई विवाद है। इसमें अयोध्या की घटनाओं का जिक्र है, लेकिन बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि से संबंधित सांप्रदायिक विवाद का कोई हवाला नहीं।

यह सब तो ठीक है, लेकिन मस्जिद में जिन १२ खंभों का इस्तेमाल हुआ है, वे गैरइस्लामिक हैं। सवाल उठता है कि क्या यह मस्जिद किसी हिंदू मंदिर के खंडहर पर बनायी गयी या इसमें किसी विध्वंसित मंदिर के मलबे का उपयोग किया गया? किसी लिखित सबूत के अभाव में इस सवाल का उत्तर देना संभव नहीं है।

ऐसा विश्वास है कि विक्रमादित्य अयोध्या आये थे और उन्होंने ८४ खंभों पर श्री राम जन्मभूमि का निर्माण किया था। आरोप है कि बाबर ने इस मंदिर को ध्वस्त करके इसके खंभों का मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया था। ये स्तंभ अब भी अच्छी हालत में हैं। ये स्याह रंग के ठोस खंभे हैं। जिस पत्थर के ये खंभे हैं, उसे स्थानीय लोग कसौटी पत्थर कहते हैं। ये खंभे तराशे हुए हैं। इनकी ऊंचाई सात से आठ फुट है। इनके नीचे का, बीच का और ऊपर का भाग चौकोर है और मध्यवर्ती भाग

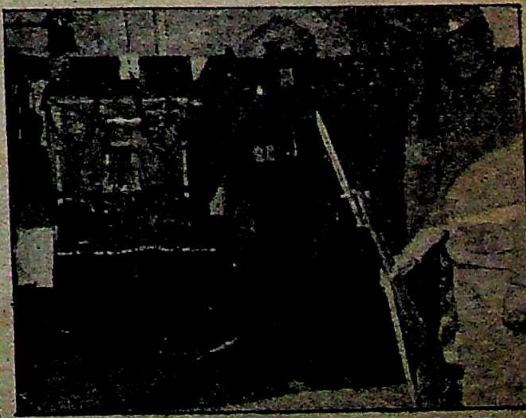
भगवान (राम जन्ममंदिर) की सुरक्षा संगीनों से

गोल या अष्टकोणीय है। ऐसे ही दो खंभे स्थानीय 'संत' मूसा आशिकान की कब्र में अधदबी अवस्था में देखे जा सकते हैं (ऐतिहासिक रिकार्ड के अनुसार इस संत का मकबरा वाराणसी में है, पर मिथक गढ़ना किसी एक समुदाय की बपौती नहीं है!)। बाबरी मस्जिद में लगे खंभों के चित्र तो हमें नहीं लेने दिये गये, लेकिन ऐसे दूसरे खंभों के चित्र हमने प्राचीन वास्तुकला के विशेषज्ञों को दिखाये। अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, सेंटर आफ आर्ट ऐंड आर्कियोलोजी, रामनगर, वाराणसी के प्रो० एम०ए० ढाके और डा० कृष्ण देव का विचार है कि ये खंभे ९ वीं और ११ वीं शताब्दी के बीच के किसी समय के हैं। यदि बाबरी मस्जिद में लगे खंभे इसी समय के हैं जैसा कि ऊपर से देखने से बिलकुल वैसे ही लगते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किसी भवन या मंदिर के ये स्तंभ कतई नहीं हो सकते। अगर इस बात को मान भी लिया जाये कि राम के जन्म-स्थल पर विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था, तो भी कहा जा सकता है कि ये खंभे उस मंदिर के बिलकुल नहीं हो सकते। यदि राम के अस्तित्व को एक ऐतिहासिक वास्तविकता मान लिया जाये, तो सवाल उठता है कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर नहीं था, तो फिर राम के जन्म का स्थल कहां है?

इस संबंध में 'अयोध्या माहात्म्य' (यात्रियों के लिए मार्गदर्शन) नामक कृति हमारी मदद करती है। 'माहात्म्य' संस्कृत में है, लेकिन 'जरनल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बेंगाल' (वाल्यूम ५४, भाग १, संख्या १ से ४-१८७५, कलकत्ता १८७५) में इसका राम नारायण द्वारा किया गया अनुवाद छपा है। अयोध्या के महाराजा मान सिंह का दावा है कि 'अयोध्या माहात्म्य' सूर्यवंश के इक्ष्वाकु की रचना है। इसके विपरीत अयोध्या के पंडित उमादत्त का कहना है कि 'माहात्म्य' 'स्कंद' और 'पद्मपुराण' का छायानुकरण है। वह यह भी कहते हैं कि इससे अयोध्या के राजा का कोई लेना-देना नहीं। पंडित उमादत्त का मत ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि 'माहात्म्य' लिखने की परंपरा १६ वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। पहला 'माहात्म्य' 'गंगा माहात्म्य' था जो १६ वीं शताब्दी के चौथे-पांचवें दशक में लिखा गया था। 'अयोध्या माहात्म्य' बाद में लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें दो बार प्रयाग को इलाहाबाद कहा गया है। अकबर (१६ वीं शताब्दी) ने प्रयाग को 'इलाहाबास' का नाम दिया था और शाहजहां (१७ वीं शताब्दी) ने इसे 'इलाहाबाद' नाम दिया था। इसलिए यह संभव है कि 'अयोध्या माहात्म्य' या तो शाहजहां के समय में या उसके बाद लिखा गया। 'माहात्म्य' में लिखा है: "स्वर्गद्वार (अयोध्या) में प्रवेश से हजारों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहां मरने वाले सभी मनुष्य, हिंदू और मुसलमान, पशु पक्षी और कीट विष्णु धाम पहुंचते हैं। विष्णु चतुर्भुजी हैं, उनकी काल जैसी आंखें हैं, वह शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी हैं और गरुड़ की सवारी करते हैं।" ('अयोध्या माहात्म्य' अनु० राम नारायण अ० चार) इस प्रकार यह शक करने के पर्याप्त कारण हैं कि यह इक्ष्वाकु की रचना है।

सार्वजनिक दान : इस तरह धन-संग्रह के अतिरिक्त, कहते हैं प्रतिदिन दस हजार रुपए के मनीआर्डर भी पहुंच रहे हैं

ऐसा लगता है कि यह 'माहात्म्य' अकबर के शासनकाल में या उसके बाद अस्तित्व में आया है। इसका कारण यह है कि अयोध्या का महत्व तुलसीकृत 'रामचरितमानस' की लोकप्रियता के साथ बढ़ा है। 'अयोध्या माहात्म्य' में राम के जन्म स्थल का दो बार जिक्र आया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी-अपनी माता के महल में जन्मे थे। एक जगह कहा गया है कि 'सीता रसोई' जन्म स्थल (कौशल्या भवन) से उत्तर-पश्चिम में स्थित है। "जन्म स्थल से चालीस गज उत्तर की ओर कैकेई भवन को 'कनक भवन' के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कैकेई ने उसे सीता को 'मुंह दिखाई' में दे दिया था। जन्मभूमि से ६० गज दक्षिण में सुमित्रा का निवास है, जहां लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। जन्म स्थल के दक्षिण पूर्व में 'सीता कूप' है, जिसे 'ज्ञान कूप' भी कहा जाता है।" (अयोध्या माहात्म्य, अध्याय १०) दूसरी जगह इसमें कहा गया है, "इसके बाद उसे (यात्री को) जन्मभूमि (राम का जन्म स्थल) में जाना चाहिए। विघ्नेश्वर के पूर्व या वशिष्ठ के निवास के उत्तर या बोमासा ऋषि की कुटिया के पश्चिम में यह जन्म स्थान है जो मोक्षदायी है, जिसको मात्र देख लेने से मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाती है।" (अयोध्या माहात्म्य, अध्याय १०)

लेकिन क्या आज जो जन्म स्थल माना जाता है वह 'अयोध्या माहात्म्य' में बतायी गयी जगह है? माहात्म्य के अनुसार जन्म स्थान मंदिर के उत्तर-पश्चिम में 'सीता रसोई' होनी चाहिए, जिससे 'कौशल्या भवन' के स्थल का भी पता चलना चाहिए, जहां राम जन्मे थे। लेकिन आज जहां 'सीता रसोई' बतायी जाती है, वह बाबरी मस्जिद (जिसे राम का जन्म स्थल कहा जा रहा है) से २०-२५ गज उत्तर-पूर्व में है (देखिए नक्शा)। इसीं तरह दशरथ की तीन रानियों के महल भी सीधे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं—'कैकेई भवन' एकदम उत्तर में है। 'माहात्म्य' के अनुसार जन्म स्थल 'कैकेई भवन' से ४० गज दक्षिण की ओर होना चाहिए। लेकिन आज जहां जन्म स्थल माना जाता है, वह स्थान (बाबरी मस्जिद) 'कैकेई भवन' से दक्षिण-पश्चिम में है। इसी प्रकार 'माहात्म्य' के अनुसार सुमित्रा का आवास भी जन्म स्थान से दक्षिण की ओर ६० गज की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन आज जहां 'सुमित्रा भवन' बताया जाता है, वह जगह बाबरी मस्जिद के दक्षिण-पूर्व में है। इसी तरह विघ्नेश्वर, बोमासा ऋषि और वशिष्ठ के आवासों से जन्म स्थान का पता लगायें, तो पाते हैं कि मस्जिद आज की स्थिति के अनुसार विघ्नेश्वर के स्थान से उत्तर-पूर्व (सीधे पूर्व में होने के बजाय) में है, बोमासा ऋषि की कुटिया से पश्चिम के बजाय उत्तर पश्चिम में है और वशिष्ठ के आवास से उत्तर के बजाय उत्तर-पश्चिम में है। वास्तव में देखा जाये, तो 'माहात्म्य' के हिसाब से मस्जिद के आस-पास कहीं 'सीता कूप' रहा होगा, क्योंकि 'सीता कूप' मस्जिद से सीधे दक्षिण-पूर्व में है। लेकिन चूंकि माहात्म्य में कुछ स्थलों की निश्चित दूरी नहीं दी गयी है और दूसरे संदर्भों में भी विसंगतियां हैं, ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि मस्जिद ठीक जन्म स्थल पर है? क्योंकि यदि दिये गये संकेतों पर विश्वास किया जाये, तो वास्तविक जन्म स्थान मस्जिद के दक्षिण-पूर्व में कहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस नतीजे पर पहुंचना तर्कसम्मत नहीं कि मस्जिद जन्म स्थान पर स्थित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां और कोई चीज न रही होगी। लेकिन वह चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि वहां और कोई हिंदू धर्म स्थल रहा हो, लेकिन क्या निश्चित रूप से वह जन्म भूमि मंदिर जैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। और यदि हिंदू धर्म स्थल नहीं था, तो वहां और क्या था?

बाबरी मस्जिद

यह धारणा १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जन्मी है कि भगवान राम के जन्मस्थल पर बने मंदिर को तोड़ कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस धारणा की जड़ें अंग्रेजों की इस रणनीति में छिपी हैं, जिसके तहत वे सांप्रदायिक टकराव को हवा देकर इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करना चाहते थे, ताकि वे अवध के विलय को अपरिहार्य और नैतिक ठहरा सकें (देखिए संलग्न कथा)। जनता के मन में सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए अंग्रेजों ने यह धारणा फैलायी कि मुगलों ने अयोध्या में हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थलों को अपवित्र किया। इसके पीछे चाल यह थी कि वे अपने को बहुसख्यकों यानी हिंदुओं के उद्धारक के रूप में पेश करना चाहते थे। मुगल, अंग्रेजों के पूर्वाधिकारी थे, इसलिए मुगलों को बलि का बकरा बनाना उनके लिए आसान था। फलतः उन्होंने इस बात को साबित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी कि मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किये और वे हिंदुओं की संस्कृति और परंपराओं के दुश्मन थे।

अंग्रेजों ने अपना मकसद पूरा करने के लिए जान लेडन को अपनी बैसाखी बनाया। १८१३ ई० में लेडन कृत ‘मेमोएर्स आफ जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, एम्परर आफ हिंदुस्तान’ (बाबर के संस्मरणों का अनुवाद) पुस्तक प्रकाशित हुई थी। लेडन ने इसमें प्रतिपादित किया था कि पठानों के खिलाफ चढ़ाई में बाबर मार्च १५२८ में अयोध्या से गुजरा था। हालांकि लेडन ने अपने अनुवाद में यह बात कहीं नहीं कही कि बाबर ने अयोध्या में हिंदू मंदिर तोड़े थे, लेकिन अंग्रेज शासकों ने इस दुष्प्रचार को प्रमाणित करने के लिए कि अयोध्या से गुजरते समय बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था, लेडन के ब्योरों का इस्तेमाल किया।

अचंभे की बात तो यह है कि अंग्रेजों के प्रचार पर किसी ने उंगली नहीं उठायी और आज भी स्थिति वही है। किसी ने भी यह सोचने की जहमत नहीं उठायी कि इस इलाके में मुस्लिम प्रभाव १०३० ई० के आसपास जम चुका था। गौरतलब बात यह है कि बाबर से पहले किसी मुस्लिम शासक में यह धार्मिक जुनून पैदा नहीं हुआ कि वह अयोध्या में बने ‘पराये-धर्म’ के मंदिरों का विध्वंस करता—खासकर उस महत्वपूर्ण मंदिर का जो राम के जन्मस्थान पर बना था। जबकि ऐसे अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि मुस्लिम (तुर्की) शासकों ने हिंदू मंदिर तोड़ कर मस्जिदें बनायी हैं। दिल्ली में

डा० जी० घोष

मतभेद को भुला देना चाहिए

हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसकी उल्लेखनीय बातें रही हैं—धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व। वास्तव में ये विशेषताएं ही भारत की पहचान हैं। यह सच है कि कुछ मौकों पर मतभेद भी उभरे हैं, लेकिन इसके लिए अंदरूनी कारणों के बजाय विदेशी ताकतें, ज्यादा जिम्मेदार रही हैं। इस भाईचारें के मानवीय गुण पर चोट करने का बहुत कुछ अपराध उन चंद लोगों ने किया है, जिन्होंने जल्दी से समृद्ध बनने की कोशिश में सामाजिक हितों को ताक पर रख दिया। लेकिन ऐसे लोगों को सिवाय उनके कौन याद करता है, जिन्होंने इन शरारती तत्वों की कारगुजारियों को भुगता है और जिनके दिमाग में इनकी आततायी की छवि अंकित है।

उक्त नजरिये से देखने पर कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि राम या रहीम के नाम पर एक बार फिर समाज को विकृत करने की कोशिश हो रही है। कई विविधताओं के बावजूद हम सदियों से साथ-साथ, खुशी-खुशी रह रहें हैं। यह देख-सोचकर देश के दुश्मनों के दिल पर सांप लोटता होगा। और दुश्मन देश के अंदर भी हैं एवं बाहर भी। नहीं तो ऐसी कौन-सी वजह है कि जिसने हमारी ‘अनेकता में एकता’ की भावना को सांप्रदायिक विद्वेष और वैमनस्य में परिवर्तित कर दिया है। दरअसल; धार्मिक कट्टरपंथियों की नयी फौज ने हमें आत्मघाती मार्ग पर ला पटका है। क्या हम इन कट्टरपंथी ताकतों पर विजय पा सकेंगे?

आधुनिक काल के महान पुरुष रामकृष्ण परमहंस ने इसको बहुत पहले महसूस कर लिया था और जिंदगी भर उन्होंने यही प्रचार किया कि हम सबकी निर्माता एक ही शक्ति है। यह धारणा इसलिए खंडित नहीं हो सकती कि हम उसे अलग-अलग नामों जैसे—राम, कृष्ण, अल्लाह, ईसा, जिहोवा (यहूदी) या जोव (यूनानी) से पुकारते हैं। जो लोग यह महसूस किये बिना कि सभी का भगवान एक है, समाज मे गड़बड़ी फैलाने में संलग्न हैं, वे कर्मकाण्डी के अलावा कुछ नहीं हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आज कुछ लोग या समुदाय किसी स्थान, इमारत या थोड़ी-सी जमीन पर अधिकार पाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये हैं।

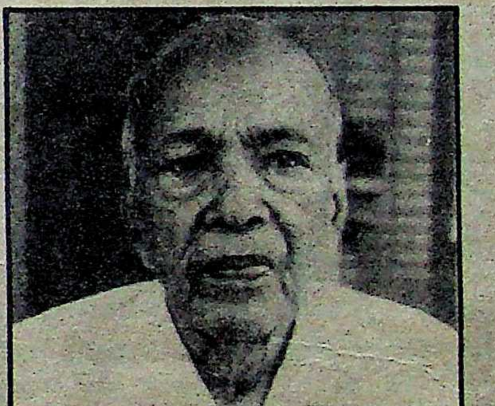

इलाहाबाद के ९३ वर्षीय डा० जी० घोष शायद भारत के सबसे बुजुर्ग डाक्टर हैं जो इस उम्र में भी चिकित्सा कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन वह यह काम समाजसेवा के तौर पर करते हैं, व्यवसाय के लिए नहीं। वह मरीजों से कोई फीस नहीं लेते। इस उम्र में भी डा० घोष मानसिक रूप से स्वस्थ और जागरूक हैं।

हाल के वर्षों में जो सांप्रदायिक विद्वेष या तनाव बढ़ा है, उसके पीछे अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद है। हम इस पूरे प्रकरण की निंदा करते हैं। यह मुद्दा या विवाद हमारे देश पर एक कलंक है और इससे हमारी भारतीयता का अपमान हुआ है। इससे दो समुदायों के बीच आपसी विश्वास में भी कमी आयी है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक धार्मिक स्थल पर किस समुदाय का हक है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि बहुसंख्यक लोग इस राजनीतिक शोषण के झांसे में आ गये हैं। आम आदमी के पास न तो इतना दिमाग है और न ही शिक्षा कि वह इन विवादों पर अपना नजरिया बना सके। भेड़िया आया, भेड़िया आया की तर्ज पर राम और अल्लाह के नाम से उनमें घृणा उपजायी जाती है।

हम २१वीं सदी की ओर जा रहे हैं। समझदार लोगों को २१वीं सदी की ओर जाते रास्ते में पैदा होनेवाली रुकावटों को भांप लेना चाहिए। आखिर हम कब तक धार्मिक अभिव्यक्ति के इस घटिया तरीके को ढोते रहेंगे? क्या हम इन बचकाने विवादों, द्वेष और सांप्रदायिक घृणा के साथ नयी सदी में जा रहे हैं?

वर्तमान समाज का गहरा अध्ययन करने से पता चलता है कि इन गंभीर मुद्दों को केवल कानूनों के जरिये सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। हमें इस तरह के समाधान पर बहुत ज्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए। बेहतर यह होगा कि सभी संबंधित समुदाय आपसी समझबूझ से इन विवादों को निपटा लें। हमें महसूस करना चाहिए कि भगवान के नाम से एक पुराने विवाद को जारी रखकर वैमनस्य, तनाव, द्वेष और घृणा को बरकरार रखना ठीक नहीं। हमें अपने पूर्व बुद्धिजीवियों के उन उपदेशों को याद करना चाहिए, जिनमें उन्होंने एकता और भाईचारे के साथ रहने को कहा था। हमें अपने मतभेद को भुला देना चाहिए।

वास्तव में अयोध्या को सभी धर्मों का तीर्थ स्थल मान लेना चाहिए। इतिहासकार इसें स्वर्णाक्षरों में लिखेंगे और यह संदेश सभी को देंगे—“राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी,” इस विशाल तीर्थ स्थल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य सभी धर्मों के लोग आयें और सच्चे भारतीयों तथा एक ही मिट्टी के सपूतों की तरह मिलें।

कुतुब भवन खंड (कांप्लेक्स), अजमेर में ढाई दिन का झोंपड़ा और गुजरात में सूर्य मंदिर इसके उदाहरण हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, इतिहास साक्षी है कि अवध में मुस्लिम-पैठ १०३० ई० से बढ़नी शुरू हो गयी थी। मिरात-ए-मसूदी (सैयद सालार मसूद की मुहिम का ब्योरा) के अनुसार सैयद सालार मसूद १०३० ई० में मुल्तान से अवध पहुंचा था। अवध पर फतह हासिल करने में उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और कुछ समय तक वह वहां रहा। १०८० ई० में सुल्तान इब्राहीम के शासनकाल में तुर्की फौजों ने नये सिरे से अवध की ओर कूच किया। इस मुहिम की कमान हाजिब तगातिन के हाथों में थी। इस मुहिम के तहत तुर्की फौजें गंगा को पार कर हिंदुस्तान में आगे तक बढ़ी थीं। सालार मसूद के काल तक कोई हमलावर इतनी दूर तक नहीं पहुंचा था। शहाबुद्दीन गोरी के नाम से चर्चित मुइजुद्दीन मुहम्मद-बिन-साम ने ११९४ ई० में कन्नौज पर कब्जा करने के बाद अवध को फतह कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि या तो उसने खुद या उसके किसी सिपहसालार ने अयोध्या को अपने आधिपत्य में लिया था। ११९४ ई० तक मुसलमानों की पहुंच अयोध्या तक हो चुकी थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि १५२८ ई० में जाकर उन्हें यह अहसास हुआ कि बिना श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़े, हिंदू धर्म को जलील नहीं किया जा सकता।

इतना ही नहीं, यह बात भी निराधार है कि बाबर और औरंगजेब ने अयोध्या के हिंदू मंदिरों को नेस्तनाबूद किया था, क्योंकि न तो कभी बाबर और न ही कभी औरंगजेब अयोध्या में पहुंचा। यह ताज्जुब की बात है कि बाबर पर यह तोहमत मढ़ी जाती है कि उसने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। 'बाबरनामा' इस बात का साक्षी है कि बाबर पक्का मुसलमान तो था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति बाबर के मन में कोई नफरत नहीं थी। १९२१ ई० में ए०एस० बेवरिज द्वारा अनूदित 'बाबरनामा: मेमोएर्स आफ बाबर' में कहा गया है कि अपनी चढ़ाई के दौरान बाबर अनेक मंदिरों में गया और उनके वास्तु-सौंदर्य की प्रशंसा की। संस्मरणों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि बाबर हिंदू मंदिरों को नष्ट करना चाहता था। न ही इस बात का कोई प्रमाण है कि बाबर ने अयोध्या में कोई हिंदू मंदिर तोड़ा। इस संदर्भ में ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कि बाबर कभी अयोध्या में पहुंचा था।

केवल लेडन के उल्लेखों ने इस धारणा को जन्म दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को बाबर ने नष्ट किया था। लेडन द्वारा अनूदित बाबर के संस्मरणों में आया है कि २८ मार्च, १५२८ में बाबर अयोध्या में था। इस धारणा को बल इसलिए मिला, क्योंकि मूल 'बाबरनामा' (इस समय इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन) के वे पृष्ठ गायब हैं, जिनमें बाबर की २ अप्रैल से ८ सितंबर, १५२८ तक की गतिविधियों का जिक्र है। लेडन ने इसीलिए यह नतीजा निकाल लिया कि बाबर इस अवधि में अयोध्या में था। लेकिन क्या वास्तव में बाबर उस समय अयोध्या में था?

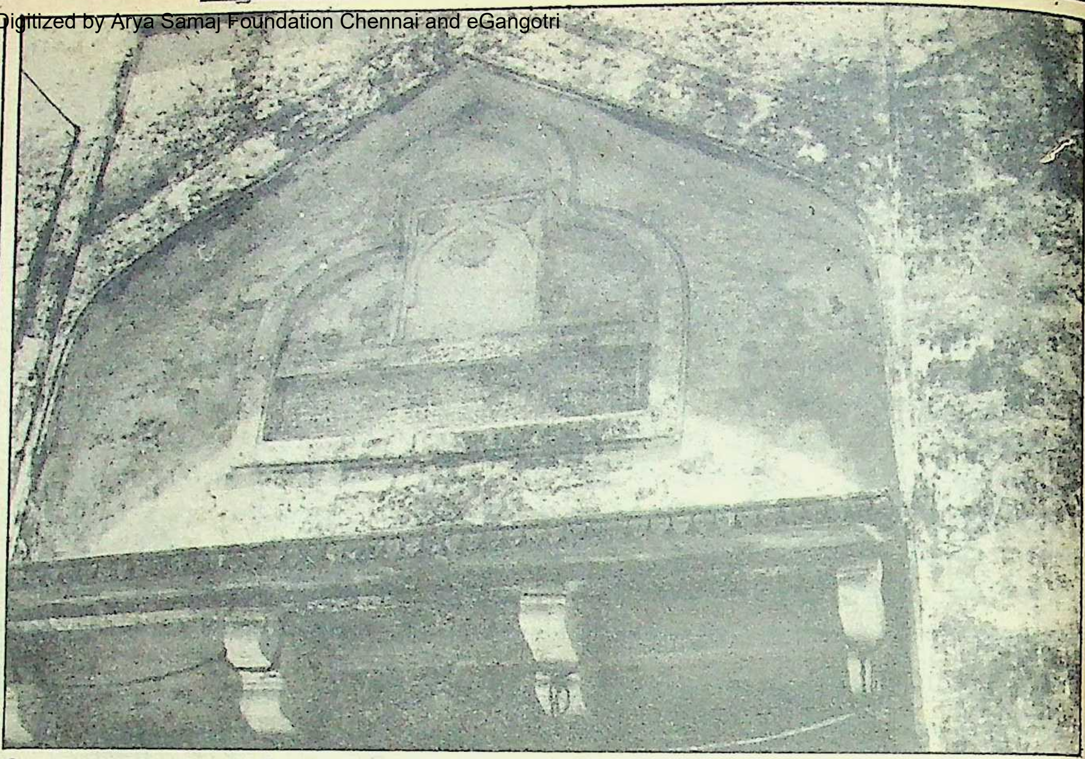

विवादास्पद इबारत: बाबरी मस्जिद का मुख्यद्वार

लगता है, जान लेडन इस क्षेत्र के भूगोल से बिलकुल अनभिज्ञ था। बाबर ने जिस असली जगह पर अपना शिविर स्थापित किया था, उस जगह की लेडन ने गलत जानकारी दी है। बाबर के अनुसार (जैसा कि लेडन ने बताया है) यह स्थान 'औद' (अयोध्या) से ४ से ६ मील उत्तर में था। बाबर सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके ब्योरों में गलती की संभावनाएं कम हैं। वह लिखता है: 'शनिवार को सातवें 'रजब' (२८ मार्च, १५२८) के दिन हमने 'औद' के ऊपर घाघर (घाघरा) और 'सिर्द' (सिरदा) के संगम से दो या तीन कोस पर पड़ाव डाला' (मेमोएर्स आफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर)। इससे लेडन ने निष्कर्ष निकाला कि बाबर ने सिर्वा (सिरदा) और घाघरा के संगम पर पड़ाव डाला। उसने घाघरा के सिर्वा घाट को सिर्वा और घाघरा का संगम समझ लिया (देखिए नक्शा)। यह हिस्सा अयोध्या के दक्षिण में १६ मील की दूरी पर है, लेकिन लेडन ने पक्का यकीन कर लिया कि बाबर ने अयोध्या के बहुत करीब पड़ाव डाला था।

इसी तरह की भौगोलिक विसंगतियां अन्य अंग्रेज इतिहासकारों के उल्लेखों में मिलती हैं। विलियम अर्स्किन ने 'हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर द टू फर्स्ट सोवरेंस आफ द हाउस आफ तैमूर, बाबर ऐंड हुमायूं'—दो वाल्यूम, लंदन, १८५४ और एच०एम० एलियट ने 'हिस्ट्री आफ इंडिया: एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस' वाल्यूम-४, १८७३ में लेडन की तरह ही लिखा है कि बाबर ने घाघरा और सिर्वा के संगम से ४-५ मील ऊपर की ओर पड़ाव डाला था। इस गलती को लेडी एनेट सुसहनाह बेवरिज ने 'बाबरनामा: मेमोएर्स आफ बाबर' १९२२, में सुधारा।

लेडी एनेट ने निष्कर्ष निकाला कि बाबर नें शारदा और घाघरा नदी के संगम से उत्तर की ओर ४-५ मील पर डेरा डाला था। उसने बाबरनामा के अनुवाद का कार्य फैजाबाद में कुछ समय तक रुकने के बाद हाथ में लिया था, जबकि लेडन ने ऐसा नहीं किया था। लेडी एनेट का विचार है कि काली-शारदा-चौका नदी ही शारदा है जो घाघरा की सहायक नदी है। इस ब्योरे को खरा मानने के तीन कारण हैं: (१) जहां घाघरा अयोध्या को छूती हुई बहती है, वहां उसें सरजू के नाम से जाना जाता है। बहराइच के पास सरजू, घाघरा में मिलती है। (२) बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि शारदा नदी सतही है और इसको पैदल पार किया जा सकता है। और (३) ज्यादातर इतिहासकारों ने औद और अयोध्या को अभिन्न माना है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सभी मुस्लिम इतिहासकारों ने गोमती और घाघरा नदियों के बीच का क्षेत्र 'औद' कहा है। इस प्रकार बहराइच में दोनों नदियों का संगम भी औद क्षेत्र में आता है।

ऐसा लगता है, इस विसंगति का कारण लिपि है। नदी के नाम में आये उर्दू के अक्षर 'दाल' को गलती से 'वाव' समझ लिया है। वैसे दोनों नदियों का संगम बाराबंकी के उत्तर में पड़ता है जो अयोध्या से ७२ मील उत्तर में है। जाहिर है कि बाबर मार्च १५२८ ई० में अयोध्या के पास नहीं था। चूंकि मूल 'बाबरनामा' के वे पृष्ठ गायब हैं, जिनमें २ अप्रैल से ८ सितंबर, १५२८ तक बाबर की गतिविधियां अंकित थीं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि बाबर कभी अयोध्या गया था। हां, यह निश्चित है कि यदि बाबर ने श्रीराम जन्मभूमि को खुद तोड़ा होता या तोड़ने का फरमान जारी किया होता, तो यह बात उसके संस्मरणों में अवश्य होती। इसलिए यह नतीजा निकाला जा सकता है कि अंग्रेज

१८५७ की संयुक्त अपील

सभी कौमों ने मिलकर आजादी के लिए कुर्बानी दी थी, अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं?

अधिकारियों ने लेडन की बात को सही मानकर यह धारणा गढ़ ली कि बाबर अयोध्या आया था और मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनवायी थी।

तार्किक ढंग से देखें, तो यह बात नहीं जमती कि जब बाबर पठानों से जूझ रहा था, तो एक मंदिर को तोड़ने के लिए उसने समय निकाला होगा। इससे वह बहुसंख्यकों की सहानुभूति खोता और अपने को कमजोर बनाता। लेकिन सभी अंग्रेज लेखकों ने यह प्रतिपादित किया है कि बाबर १५२८ में अयोध्या आया था और वहां एक सप्ताह के लिए रुका था तथा उसने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर अपने नाम पर मस्जिद बनायी थी। इन इतिहासकारों में पी० कारनेगी (ए हिस्टोरीकल स्केच आफ फैजाबाद तहसील, इनक्लूडिंग द फोरमर कैपिटल्स आफ अयोध्या ऐंड फैजाबाद, अलाहाबाद १८६१), डब्ल्यू०सी० बेनेट (गजेटियर आफ द प्रोविंस आफ अवध, ३ वाल्यूम, कलकत्ता १८७७), ए० फ्यूहरर (रिपोर्ट आफ द आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, (इंपीरियल सिरीज), द मोनुमेंटल एंटीक्वीटीज ऐंड इंस्क्रिप्शंस इन द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऐंड अवध-२ वाल्यूम १९०१) और एच०आर० नेविल (डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ द यूनाइटेड प्रोविंसेज आफ आगरा ऐंड अवध, फैजाबाद, वाल्यूम ६३ अलाहाबाद १९०५) आदि शामिल हैं।

इन अंग्रेज इतिहासकारों के विपरीत ए० कनिंघम ने इस बात को तो माना है कि 'मुसलमानों' द्वारा अयोध्या में पुराने मंदिरों को नष्ट किया गया, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि स्वयं बाबर ने ऐसा कोई विध्वंस किया था। यह बात कनिंघम ने 'रिपोर्ट आफ द आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया' वाल्यूम-एक, १८६४ ई०-में कही है। इस बात का किसी ने अभी तक खंडन भी नहीं किया है। कनिंघम कहता है: "अयोध्या में अनेक पवित्र हिंदू मंदिर हैं, लेकिन वे सभी हाल के हैं और उनकी वास्तुकला कोई उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये मंदिर उन प्राचीन मंदिरों की जगह बने हैं, जिनको मुसलमानों ने तहस-नहस कर दिया था। नगर के पूर्व में 'रामकोट' या 'हनुमान गढ़ी' है जो छोटी दीवारों का एक किला है। वह एक पुराने टीले पर बने आधुनिक मंदिर को घेरे हुए है। निश्चित रूप से 'रामकोट' प्राचीन नाम है, क्योंकि यह 'मणि पर्वत' की परंपरा से संबद्ध है। ...लेकिन हनुमान मंदिर औरंगजेब के समय से पहले का नहीं है।"

इसके बावजूद यह विवाद जारी है कि राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी। इसका कारण है मस्जिद पर लिखी इबारतें और गैरइस्लामिक खंभे। इबारतें साफ बताती हैं कि मस्जिद १५२९ में बनायी गयी। लेडी ए०एस० बेवरिज का मत है कि मस्जिद बाबर के फरमान से बनी। दरअसल इबारत में है कि मस्जिद अमीर मीर बांकी ने बनवायी थी जो बाबर के दरबार में एक अमीर था और जिसे बाबर ने अवध का राज्यपाल नियुक्त किया था। लेडी बेवरिज लिखती हैं, "शायद मस्जिद के निर्माण का आदेश बाबर ने औद (अयोध्या) में आवास के समय ९३४ अलहिजरी में दिया। उस समय वह हिंदू मंदिर की गरिमा और पवित्रता से आकर्षित हुआ होगा। उसने मंदिर को तोड़ा (एक भाग)। मोहम्मद के आज्ञाकारी अनुयायी के नाते वह भी दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु था और उसने मंदिर की जगह एक मस्जिद बनाना अपना कर्तव्य समझा। मस्जिद ९३५ अलहिजरी में बनकर तैयार हुई। लेकिन 'बाबर नामा' में इसके पूर्ण होने का कोई जिक्र नहीं है। ९३५ अलहिजरी की डायरी में कई खामियां हैं। एक तो ९३४ अलहिजरी (बाबरनामा का उस समय का अंश) की बहुत सी सामग्री खो गयी है, खासकर जहां औद का वर्णन शुरू होना था, उससे पहले की।" (ए०एस० बेवरिज द्वारा अनूदित बाबरनामा, १९२२ परिशिष्ट ७७)। ऐसा लगता है कि लेडी बेवरिज प्रचलित स्थानीय विश्वासों से प्रभावित हुई है।

यह आश्चर्य की बात है कि न तो 'बाबरनामा' और न ही मस्जिद की इबारतें (अभिलेख) इस बात की ओर संकेत करती हैं कि श्रीराम जन्मभूमि को स्वयं बाबर ने या उसके किसी आदमी ने नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया है। यद्यपि इबारतों को देखने पर भी कई तरह के शक-शुबहे होते हैं। यहां तीन इबारतें हैं। दो बाबरी मस्जिद के बाहर और एक अंदर मिम्बर (इमाम के खड़े होने की जगह) के ऊपर। बाहर की दो इबारतों में एक छह पंक्तियों की है और दूसरी एक पंक्ति की। ये इबारतें शेरनुमा हैं। छह पंक्तियों वाली इबारत में पहली पंक्ति है: "बा-फर्मूदह-शाह बाबर की अदिलश"।

बेवरिज ने अपने अनुवाद में 'बा-फर्मूदह-शाह बाबर' का मतलब सम्राट बाबर के आदेश से लगाया है। लेडी बेवरिज की यह व्याख्या गलत हैं। यह गौरतलब है कि विजेताओं के अधीन सारी जमीन शासक की मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में चाहे इमारत कोई भी बनवाये, उसके साथ तत्कालीन सम्राट का नाम जुड़ना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। इसलिए संभव है मीर बांकी ने अपने उत्साह में सम्राट को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या की मस्जिद को बाबर को समर्पित करने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि उपलब्ध दस्तावेजों में किसी ऐसे शाही फरमान का वजूद नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि बाबर ने मस्जिद के निर्माण का हुकुम दिया था। (उदाहरण के लिए, दूसरी मस्जिदों में निर्माण के समय ऐसा हुआ है। दिल्ली के पुराने किले के पास बनी बाबरी मस्जिद के निर्माण का फरमान रिकार्ड में उपलब्ध है) इसके अलावा भी मस्जिद के बाहर की इबारतों की लिखावट-शैली और शब्दावली से भी अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। फारसी के विद्वान और विख्यात उर्दू आलोचक शमशुर रहमान फारूकी का मत है कि बाबर का यदि स्पष्ट आदेश रहा होता, तो इसकी (बाहरी इबारत की) शब्दावली ऐसे होती: 'बा हुक्म मोहम्मद जहीरुद्दीन गाजी बाबर' न कि 'बा-फर्मूदह-शाह बाबर', जिसका मतलब होता है शहंशाह बाबर की इच्छा से। उक्त विद्वान का विचार है कि लिखावट की शैली १९वीं शताब्दी की है, जबकि पहले की शैली में नफीस सतरें होती थीं। इस लिखावट में मोटी रेखाएं हैं, जिससे जाहिर होता है कि यह बाद की लिखावट है। वह यह भी महसूस करते हैं कि ये इबारतें किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखवायी हैं, जो फारसी ठीक से नहीं जानता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इबारतें मंदिर-मस्जिद विवाद के पैदा होने के बाद किसी ने

१९वीं शताब्दी में लिखवायीं। वह व्यक्ति शायद यह साबित करना चाहता था कि यह मस्जिद बाबर के हुक्म से बनी है।

लेकिन बाबर का नाम ही क्यों उछाला? साफ है कि इसके पीछे उस विश्वास को पुष्ट करना था, जिसके तहत यह धारणा थी कि मार्च १५, १५२९ (जब मस्जिद बनकर पूरी हुई) में बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया था। यह निष्कर्ष मस्जिद के अंदर मिम्बर के ऊपर छंदबद्ध तीन पंक्तियों पर नजर दौड़ाने पर तर्कसंगत प्रतीत होता है। पहली पंक्ति में खुदा की प्रशंसा है और दूसरी पंक्ति में पैगंबर मोहम्मद का गौरवीकरण है, जबकि तीसरी पंक्ति में बाबर की एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में बड़ाई की गयी है। इन पक्तियों में कहीं भी बाबर के आदेश का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य दो इबारतों में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर या कोई अन्य हिंदू मंदिर था।

मस्जिद का वास्तुशिल्प भी काफी रोचक है। इस मस्जिद का निर्माण खास शर्की शैली में किया गया है। जौनपुर के शर्की राजा अपने भवनों के निर्माण के लिए भारतीय राजगीरों का इस्तेमाल करते थे। इस कारण वे निर्दोष मेहराब बनाने में असमर्थ थे। ज्यादातर शर्की स्मारकों के मेहराब खास तरीके के बने हुए हैं और वे लट्ठे पर टिके हैं। इसके अलावा इस मस्जिद का गुंबद भी वास्तुकला की शर्की शैली का ही नमूना है। दरअसल अगर बाबरी मस्जिद को पीछे से (पश्चिम की ओर से) देखा जाये, तो जौनपुर की अटाला मस्जिद से मेल खाती है। यहां यह बात भी गौरतलब है कि पंद्रहवीं शताब्दी तक दिल्ली में तुर्कियों ने गुंबद बनाने की शैली विकसित कर ली थी। मेहराब बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन यह सुधार उस मस्जिद में कहीं नहीं दिखायी पड़ता। अगर मस्जिद सोलहवीं शताब्दी में बनी होती, यानी बाबर के समय में, तो निश्चित रूप से उस समय तक स्थापत्य कला में हासिल की गयी महारत इसमें दिखायी पड़ती।

उल्लेखनीय है कि बाबरी मस्जिद के उत्तरी दरवाजे पर एक खास प्रतीक अंकित है। दरवाजे के ऊपर आमने-सामने दो बाघ हैं। ये छलांग लगाने की मुद्रा में हैं और इनकी पूंछ बल खाती हुई है। दो बाघों के बीच में एक सीधा मोर है। ठीक इसी तरह के बाघ शर्की राजा के सिक्कों पर अंकित हैं। इतिहास साक्षी है कि १३७६ ई० में अवध की रियासत मलिक हिसामुल मुल्क और हिसामुद्दीन नावा के अधीन थी। इसके काफी बाद, फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न अस्थिरता के दौरान, अफगान सरदारों ने स्वतंत्र रियासतें स्थापित करने का प्रयास किया था। १३९४ के आसपास वजीर ख्वाजा-ए-जहां ने अवध और बिहार तथा कन्नौज के बीच पड़ने वाले संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, जिसे जौनपुर की शाही रियासत का रूप दिया गया। दिल्ली के गृहयुद्ध के दौरान उसने अपनी स्थिति और मजबूत

साक्षात्कार/शहाबुद्दीन

इस केस को दक्षिण भारत के किसी न्यायालय को सौंप देना चाहिए

ऐसे एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं हैं जिनसे यह साबित होता है कि बाबर या उसके नुमाइंदे मीर बांकी ने किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। सीधी सी बात है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद स्थित है। वैष्णवों के अनुसार राम जन्मस्थली मंदिर बाबरी मस्जिद के उत्तर में स्थित है, न कि इसके अंदर। यह सच है कि मस्जिद के बाहरी हिस्से में राम चबूतरा है, लेकिन मस्जिद से यह बिलकुल अलग है।

ऐतिहासिक रूप में उत्तरी भारत में राम भक्ति की शुरुआत केवल ४०० साल पहले हुई थी। बाबरी मस्जिद के निर्माण के २५ साल बाद ही तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी थी, लेकिन उन्होंने किसी राम जन्मभूमि मंदिर तोड़े जाने का जिक्र अपने ग्रंथ में नहीं किया। वास्तव में भारत में ऐसा कोई राम मंदिर नहीं है जो ४०० साल पुराना हो। जैसा कि बाबर भारत में १५२६ ई० में आया था, इसलिए उसके द्वारा कोई मंदिर तोड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता।

हिंदू धर्मावलंबियों का कहना है कि वास्तुकला के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि विवादास्पद स्थल मस्जिद है। वे कहते हैं कि अन्य मस्जिदों की भांति बाबरी मस्जिद में गुंबद नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हर मस्जिद में गुंबद होना जरूरी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में स्थित शेरशाह के मकबरे में गुंबद नहीं है। वास्तव में मस्जिद में एक बरामदा होना चाहिए, जिसमें पश्चिम की ओर (मक्का की ओर) मुंह करके नमाज अदा की जा सके। बाकी वास्तुकला विवरणों को जाने दीजिए।

हिंदुओं द्वारा यह भी कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की संरचना बिलकुल 'हिंदू' मंदिरों-सी है और उसमें हिंदू चिह्न अंकित हैं। लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि इस्लाम में कलाओं में चूंकि मनुष्य या जानवरों के चित्र बनाने की मनाही है, इसलिए फूल (बेल) और ज्यामितीय रेखांकन का सहारा लिया जाता है। बाबरी मस्जिद में कमल भी इसीलिए बना है।

एक और हिंदू सिद्धांत के अनुसार मस्जिद के खंभे बहुत पुराने और पोले हैं, जिसका मतलब है कि उनका उपयोग सजावट के लिए किया गया था न कि सहारे के लिए। यह सच है, पर इससे क्या? यह बहुत संभव है कि ये खंभे किसी खण्डहर (नष्ट इमारत) से लाये गये हों, जैसा कि आज भी किया जाता है।

मंदिर या मस्जिद के निर्माण में जिस आधारभूत सिद्धांत को अपनाया जाता है उसे ध्यान में रखना चाहिए। मस्जिद के निर्माण में मुख्य हिस्सा पश्चिम की तरफ और खाली जमीन उसके सामने यानी पूर्व में होती है, जबकि मंदिर में मुख्य हिस्सा मध्य में और खाली जमीन उसके चारों ओर होती है। बाबरी मस्जिद भी मस्जिद की तर्ज पर निर्मित हुई है, जिसे स्पष्टत: देखा जा सकता है।

१३ वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिमों के आने के पूर्व अयोध्या बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान था। गुप्त काल और १३ वीं सदी में भारत आये प्रसिद्ध चीनी यात्रियों की पुस्तकों से यह सिद्ध भी किया जा सकता है।

बहरहाल, यह विवाद धर्म की अपेक्षा राजनीति की देन ज्यादा है। यह स्थिति जान-बूझकर १९८० के दौरान इंदिरा गांधी ने पैदा की थी, जिसे १९८६ में इस विवादास्पद स्थल का ताला खुलवाकर उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी जारी रखा। इस समस्या को सुलझाने के लिए विवाद की जड़ में जाना होगा, जो कि इस बात से तय होगा कि यह मंदिर है या मस्जिद। यह मामला फैजाबाद की अदालत में पिछले ३७ सालों से अटका है। यदि आपसी बातचीत से या राजनीतिक मध्यस्थता के जरिये मामला नहीं सुलझता तो फिर इसे अदालत के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जनहित को देखते हुए चूंकि फैसला जल्दी होना चाहिए इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को पहल करनी चाहिए और मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश देने चाहिए। खास तौर पर दक्षिण भारत के उच्च न्यायालय में। मैं दक्षिण भारत को इसलिए प्रमुखता दे रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में दक्षिण भारतीय हिंदू अच्छे हिंदू हैं और दक्षिण भारतीय मुसलमान अच्छे मुसलमान। बहरहाल, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाने में क्यों हिचकिचा रही है? किसी भी समस्या के समाधान का यह सबसे अच्छा तरीका है। कम-से-कम मैं तो देश के न्यायालय के फैसले को मानूंगा।

—प्रस्तुति: प्रकाश नंदा

की और स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। बहुत संभव है कि आज जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उसका निर्माण इसी समय के आसपास—यानी १४वीं शताब्दी में हुआ होगा। यह भी अचंभे की बात है कि बाबर जैसा सौंदर्य-प्रेमी ऐसी अनाकर्षक मस्जिद के निर्माण के लिए सहमत हो गया, जिसका वास्तु सौंदर्य कोई महत्व नहीं रखता। इस विवाद को उछालने वाले लोगों ने ऐसा लगता है कि इस बात को बिना तर्क पर कसे ही स्वीकार कर लिया कि मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी हुई है। अंग्रेज लेखकों का तर्क है कि अयोध्या में हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के पीछे भारत में इस्लाम का विस्तार करना था। लेकिन यह तर्क बिलकुल लचर है, क्योंकि विवादास्पद स्थान पर नमाज पढ़ने का कतई विधान नहीं है। जाहिर है, यदि मंदिर की जगह मस्जिद बनी होती, तो मस्जिद बनाना निरर्थक था, क्योंकि इसमें नमाज तो पढ़ी नहीं जा सकती थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंदिर को तोड़ने के बाद इसके आसपास किसी जगह पर मस्जिद बनायी जा सकती थी। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वाराणसी और मथुरा में बनी विवादास्पद मस्जिदें ठीक उस जगह पर नहीं बनी हो सकतीं जहां पहले मंदिर थे। तोड़े गये मंदिर के निकट तो मस्जिद बनायी जा सकती है, लेकिन ठीक उसी स्थान पर मस्जिद बनाना नामुमकिन है। यह धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जबकि इस तरह के धर्म-स्थानों के निर्माण का लक्ष्य होता है—धर्म का प्रचार करना। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि बाबर जैसा पक्का मुसलमान और कुरान का ज्ञाता कहीं ऐसी गलती कर सकता था कि वह अपने नाम पर उस जगह मस्जिद बनाता जिस जगह एक महत्वपूर्ण मंदिर था? तो फिर वहां क्या था?

तोड़े गये मंदिर के निकट तो मस्जिद बनायी जा सकती है, लेकिन ठीक उसी स्थान पर मस्जिद बनाना नामुमकिन है। यह धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जबकि इस तरह के धर्म-स्थानों के निर्माण का लक्ष्य होता है—धर्म का प्रचार करना। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि बाबर जैसा पक्का मुसलमान और कुरान का ज्ञाता कहीं ऐसी गलती कर सकता था कि वह अपने नाम पर उस जगह मस्जिद बनाता जिस जगह एक महत्वपूर्ण मंदिर था? तो फिर वहां क्या था?

बौद्ध-स्मारक

१८६२ और १८६५ ई० के बीच, कनिंघम ने उत्तरी भारत में अनेक पुरातात्विक सर्वेक्षण किये। उनका मूल लक्ष्य उन स्थानों का पता लगाना था, जहां-जहां चीनी यात्री फाह्यान व ह्वेनसांग ने यात्राएं की थीं। फाह्यान ४०० और ४१० ई० के बीच और ह्वेनसांग ६९२ ई० में भारत आया था। कनिंघम को यह विश्वास हो गया कि 'शा-ची' नामक स्थान, जिसका जिक्र फाह्यान ने किया है और 'विशाखा' नामक स्थान, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है—दोनों एक ही स्थान के नाम हैं और जिस भौगोलिक स्थान की दोनों चीनी यात्रियों ने चर्चा की है, वह और कोई नहीं साकेत या अयोध्या ही है।

कनिंघम के अनुसार, "शा-ची के बारे में चर्चा करते हुए फाह्यान ने कहा है, 'इस नगर के दक्षिणी द्वार से बाहर निकल कर सड़क के पूरब की ओर वह स्थान है, जहां बुद्ध ने अपनी दातुन का एक टुकड़ा फेंक दिया था, जिसने धीरे-धीरे सात फुट ऊंचे पेड़ का रूप धारण कर लिया और उसके बाद वह न कभी घटा न बढ़ा।' इसी किंवदंती की चर्चा 'विशाखा' के बारे में ह्वेनसांग ने भी की है। उनके अनुसार 'नगर के दक्षिणी ओर तथा सड़क के बायीं ओर (यानी सड़क के पूरब की ओर, जैसा फाह्यान ने कहा है) अन्य पवित्र चीजों के अतिरिक्त एक ६ या ७ फुट ऊंचा पेड़ था जो न कभी बढ़ता था न घटता था।' बुद्ध के दातुन के पेड़ के बारे में एक और सबूत है। इस पेड़ के संबंध में फाह्यान व ह्वेनसांग ने एक-ही जैसा वर्णन किया है। इससे मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह जाता कि दोनों चीनी यात्री एक ही नगर की चर्चा कर रहे थे, यद्यपि एक ने उसे 'शा-ची' कहा और दूसरे ने 'विशाखा'।

"विशाखा ही साकेत या अयोध्या है, यह प्रमाणित करने के लिए मैंने निम्नलिखित तथ्यों का सहारा लिया है, जो इस प्रकार हैं: १—बौद्ध इतिहास में 'विशाखा' उन प्रख्यात महिलाओं में एक रही है जो साकेत निवासी थी। उसका विवाह श्रावस्ती के धनी व्यापारी मृगार के पुत्र पूर्णवर्द्धन से हुआ था। २—ह्वेनसांग के अनुसार बुद्ध ने 'विशाखा' में छह वर्ष व्यतीत किये, जबकि पालि इतिहास के अनुसार वह साकेत में १६ वर्ष रहे।"

प्रचीन भारत के भूगोल के माने-जाने ज्ञाता प्रो० बी०सी० ला ने भी कनिंघम के मत का समर्थन किया है। अपनी पुस्तक 'इण्डोलाजिकल स्टडीज, भाग ३, अध्याय २, इलाहाबाद, १९५४' में उन्होंने कहा है, "अयोध्या, अयोज्झा या अयुधा हिंदुओं के सात पवित्र स्थानों में एक है। फाह्यान ने इस नगर को 'शा-ची' कहा है, और टोलोमी के अनुसार, यह सोगडा के नाम से जाना जाता है...यह नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है...यह वैष्णवों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। पालि साहित्य में उल्लिखित सरयू या 'सरभू' अवध की घाघरा अथवा गोगरा ही है।"

कनिंघम अपने इस विश्वास पर अडिग रहा कि गौतम बुद्ध ने साकेत (अयोध्या) में निवास किया था। बौद्ध-संबंधी सीलोन (श्रीलंका) व बर्मा के इतिहास के अनुसार, बुद्धत्व प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध ३५ वर्ष के थे। तत्पश्चात, २० वर्षों तक उन्होंने संन्यासी जीवन बिताया और उत्तर भारत में जगह-जगह धर्मोपदेश देते रहे। इन स्थानों का जिक्र उपर्युक्त इतिहास में आता है। इसी इतिहास का उद्धरण देते हुए कनिंघम कहता है (आर्कियोलाजिकल रिपोर्ट, पृष्ठ ३१९):

"२० वर्ष तक धर्मोपदेश देने के बाद बाकी के २५ वर्ष उन्होंने बौद्ध मठों में बिताये। ९ वर्ष श्रावस्ती के 'जेतवन' मठ में और १६ वर्ष साकेतपुर के 'पुभरमो' (पुष्पाराम) मठ में, जबकि बर्मी इतिहास में, १९ वर्ष और ६ वर्षों का उल्लेख है। ह्वेनसांग ने भी ६ वर्ष का ही उल्लेख किया है। बुद्ध के निवास के बारे में यह एक अकाट्य प्रमाण है। तदनुसार केवल दो ही स्थान थे, जहां बुद्ध ने निवास किया, पहला—श्रावस्ती जहां वह ९ या १९ वर्ष रहे और दूसरा, 'साकेत' जहां विशाखा में उन्होंने ६ वर्ष तक निवास किया। विशाखा श्रावस्ती से दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर स्थित है। इस तरह, यह निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से निकलता है कि 'विशाखा' व 'साकेत' एक ही स्थान के दो नाम हैं।"

अयोध्या के भू-दृश्य की चर्चा करते हुए कनिंघम ने पाया कि नगर में अनेक टीलों का अस्तित्व काफी अर्थपूर्ण है। अपनी आर्कियोलाजिकल रिपोर्ट (१८६२-६३, पृष्ठ ३२२) में वह कहता है:

"अयोध्या के अवशेषों में जो सर्वाधिक प्राचीन चीजें प्रतीत होती हैं, वे हैं—शहर के दक्षिण में करीब पौन मील की दूरी पर स्थित मिट्टी के तीन टीले। इनके नाम हैं—'मणि पर्वत,' 'कुबेर पर्वत' और 'सुग्रीव पर्वत'। इन तीनों टीलों के साथ हम उस टीले पर भी ध्यान केंद्रित करें, जिस पर बाबरी मस्जिद स्थित है। बाबरी मस्जिद, शहर के बिलकुल बीचोबीच एक मिट्टी के टीले पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई पूरब की ओर २० फुट और पश्चिम की ओर ४० फुट है। अगर पश्चिम की ओर से देखा जाये, तो यह टीला उन अनेक पर्वतों की तरह है जो अयोध्या में दिखते हैं।"

इन पर्वतों के बारे में कनिंघम कहता है, "ब्राह्मणों का यह विश्वास है कि 'मणि पर्वत' उन पहाड़ियों में एक है जिसे बंदरों ने राम के सहायतार्थ बनाया था। दुर्घटनावश, वह किष्किधा के राजा सुग्रीव के हाथों से छूट कर यहीं पर गिर पड़ा था।...इस टीले के दक्षिण की ओर ५०० फुट की दूरी पर 'कुबेर पर्वत' स्थित है जिसकी ऊंचाई केवल २८ फुट है। इसका धरातल, पुरानी ईंटों के कूड़े-कर्कट के कारण, ऊबड़-खाबड़ दिखता है और कहीं-कहीं गड्ढे भी दिखते हैं जो संभवतः लोगों द्वारा ईंटों के लिए खुदाई करने की वजह से बन गये हैं। ईंटों का आकार बड़ा (११ इंच x७.५x२) है। दक्षिण-पूर्व की ओर एक बड़ा आयताकार टीला है जिसे 'सुग्रीव पर्वत' के नाम से जाना जाता है। जमीन से यह केवल

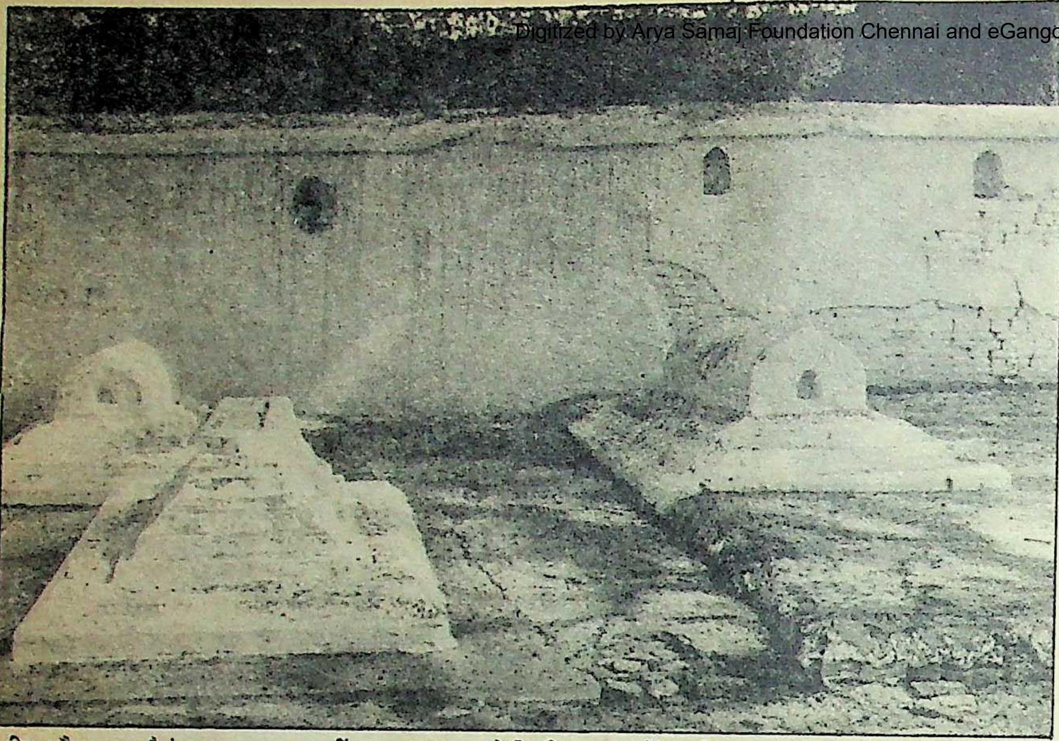

सीस और अयूब पैगंबर का मजार : कनिंघम का कहना है कि जिन चबूतरों पर ये मजार बने हुए हैं, वे चबूतरे चार बुद्धों के बैठने का आसन था। यह भी उल्लेखनीय है कि चबूतरे पर स्थित मजार की आयु और चबूतरे की आयु में स्पष्ट अंतर नजर आता है। यह अंतर चबूतरे में लगी ईंटों से भी पता चलता है। चबूतरे की ईंटें और चहारदीवारी में लगी ईंटों में स्पष्ट रूप से आयु-भेद है। इतना ही नहीं, चहारदीवारी में लगी ईंटों में भी आयु-भेद है। नीचे लगी ईंटें और उसके बाद परत-दर-परत ईंटों में जाहिरा भेद है।

८ या १० फुट की ऊंचाई पर है। 'मणि पर्वत' व 'कुबेर पर्वत' के बीच एक मुस्लिम अहाता है जो पूरब से पश्चिम की ओर ६४ फुट लंबा और ४७ फुट चौड़ा है। इस अहाते में ईंटों के दो मकबरे हैं और कहा जाता है कि ये सीस और अयूब पैगंबरों के हैं, जिन्हें पैगंबर सेठ व जाब के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदुओं की तरह अयोध्या के स्थानीय मुसलमान भी अनेक मिथकों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, सीस पैगंबर और अयूब पैगंबर के मकबरों के बारे में कही जाने वाली कहानियां इसी बात की प्रतीक हैं। इन मकबरों में पहले की लंबाई इस समय २१ फुट और दूसरे की १२ फुट है। यह विचित्र बात है कि समय-समय पर इनकी लंबाई में इजाफा होता रहा है। इस संबंध में अबुल फजल ने 'आईने अकबरी' में लिखा है-''इस नगर के पास दो स्मारक हैं, एक सात और दूसरा छह हाथ लंबा। जनसाधारण इन्हें पैगंबर सेठ व जाब का मकबरा मानते हैं और उनसे संबंधित अनेक चमत्कारी कहानियां भी सुनाते रहते हैं।''

दूसरी ओर १८६३ में कनिंघम ने इन दोनों मकबरों की लंबाई क्रमश: १७ फुट व १२ फुट बताती है। इससे जाहिर है कि सीस पैगंबर के मकबरे की लंबाई जो अबुल फजल के समय साढ़े दस फुट थी, वह बढ़कर कनिंघम के समय में (१८६३ में) १७ फुट हो गयी और अब (१९८७ में) यही २१ फुट है।

कनिंघम का यह मत था कि ये मकबरे वास्तव में सीस और अयूब पैगंबरों के न होकर उन सैनिकों के हैं जो प्रारंभिक तुर्की आक्रमणकारियों के साथ यहां आये और मारे गये। इस्लामी परंपरा में मृत सैनिकों को सड़क के किनारे ही दफना दिया जाता था। कनिंघम के अनुसार मकबरों में लगी ईंटें काफी प्राचीन हैं। अत: उनको यकीन हो गया कि यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने दातुन का पेड़ लगाया था। वह कहता है :

''फाह्यान के अनुसार वह स्थान जहां बुद्ध का पावन पेड़ उपजा था, वह सड़क से पूरब की ओर था जो नगर के दक्षिण द्वार की ओर है। ह्वेनसांग ने भी इसी स्थान का जिक्र किया है—'पेड़ नगर के दक्षिण की ओर तथा सड़क के बायीं ओर स्थित है।'...यह ध्यान देने योग्य बात है कि टीले जो अब भी टूटी-फूटी स्थिति में मौजूद हैं, शहर के दक्षिणी सड़क के बायीं ओर हैं। अत: स्थिति निस्संदेह वैसी ही है जैसी कि चीनी यात्रियों ने वर्णित की है। चूंकि इन टीलों की स्थिति ह्वेनसांग द्वारा वर्णित ब्योरे से पूरी तरह मिलती है, इसलिए उनकी पहचान के बारे में किसी प्रकार का शक बाकी नहीं रह जाता।''

कनिंघम का यह भी विश्वास है कि अहाते के अंदर चार मकबरे (दो सीस व अयूब पैगंबरों के और दो अयूब पैगंबर के पुत्रों के) उन्हीं चार चबूतरों पर बनाये गये हैं, जहां पर चार पूर्ववर्ती बुद्ध अपना आसन लगाते थे। कनिंघम कहता है :

''ह्वेनसांग ने अपने विस्तृत वर्णन में बुद्ध के पावन दातुन-पेड़ और चार चबूतरों के बारे में चर्चा करते हुए लिखा है कि ये दोनों एक विशाल स्तूप के निकट हैं। ये स्थान और कहीं नहीं, बल्कि उसी अहाते में स्थित थे, जहां अब पैगंबर सेठ व जाब के मकबरे हैं। यह अहाता मणि पर्वत के दक्षिणी किनारे को स्पर्श करता है। ये दोनों मकबरे पूर्ववर्ती चार बुद्धों के आसन के ही अवशेष हैं...''

जिस विशाल स्तूप की ऊपर चर्चा की गयी है, कनिंघम के अनुसार वह सम्राट अशोक का स्तूप था। कनिंघम के अनुसार यह स्तूप २०० फुट ऊंचा था और उसी स्थान पर बनाया गया था, जहां साकेत (अयोध्या) में अपने छह वर्षीय निवास के दौरान बुद्ध ने धर्मोपदेश दिये थे। कनिंघम के अनुसार, ''यही 'मणि पर्वत' है, जो अभी भी ६५ फुट ऊंचा है, उसकी बनावट को देखते हुए वह इतना ही और ऊंचा रहा होगा और यदि उसकी धातु-शिखर की लंबाई को भी ध्यान में रखा जाये, तो स्तूप की कुल ऊंचाई निस्संदेह २०० फुट तक होगी। ह्वेनसांग के अनुसार इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था, और इसे गलत मानने के लिए मेरे पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आधा मिट्टी और आधा पक्का होने से यह नि:संदेह काफी प्राचीन ही होगा, संभवत: ईसा से पांच शताब्दी पूर्व का। मेरा विश्वास इस तथ्य पर आधारित है कि अशोक के युग के सभी स्मारक, जिनका जिक्र ह्वेनसांग ने किया है और जिन्हें भिलसा के निकट मैंने अपनी खुदाई में पाया, वे या तो पत्थर के बने थे या ईंट के। अत: मिट्टी के टीले इस बात का संकेत करते हैं कि स्तूप और भी पहले बना था, परंतु किसी भी स्थिति में वह ईसा से पांच शताब्दी पूर्व का नहीं हो सकता। अयोध्या में स्थित 'मणि पर्वत' के बारे में मेरा यह निष्कर्ष है कि—टीला और उसका निम्न भाग बौद्ध धर्म के प्रारंभिक युग में बनाया जाना सिद्ध करता है। उसका ऊपरी भाग बाद में अशोक द्वारा जुड़वाया गया था। 'मणि पर्वत' के अधोभाग से मुझे एक ईंट का एक अंश मिला, जिस पर अतिपुरातन 'श' अक्षर अंकित था। परंतु, चूंकि यह अशोक-युग के काफी बाद का है, इसलिए वह ईंट मूलत: 'मणि पर्वत' की नहीं लगती।''

बहुत हद तक कनिघम उन स्थानों को पहचानने में सफल हुआ, जिनका फाह्यान व ह्वेनसांग ने जिक्र किया है। ह्वेनसांग के अनुसार अयोध्या में बौद्ध धर्म और हिंदुओं की अनेक स्वस्थ परंपराएं विद्यमान थीं, वहां पर ३००० बौद्ध भिक्षुओं वाले २० बौद्ध मठ और ५० सनातनी हिंदू मंदिर थे। ह्वेनसांग ने एक ऐसे मठ का भी विस्तृत ब्योरा दिया है जो या तो साकेत का 'कालकाराम' या 'पूर्वाराम' मठ था। दोनों का जिक्र सीलोन के 'महावंसो' में भी आता है। कनिंघम के अनुसार यह मठ ही अब 'सुग्रीव पर्वत' के रूप में विद्यमान है, जिसके बगल में अशोक का स्तूप है।

कनिंघम कहता है, ''जिस पहले स्मारक का जिक्र ह्वेनसांग ने किया है, वह एक अनाम विशाल मठ है, परंतु चूंकि अपनी विशालता के कारण यह एक विशिष्ट मठ था, संभवत: यह साकेत का 'कालकाराम' अथवा 'पूर्वाराम' मठ रहा होगा, जिसका जिक्र सीलोन के 'महावंसो' में आता है। इस मठ के वासी 'सम्मतीय' मठ के थे और यह मठ तीन विख्यात बौद्ध तर्कवादियों को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान 'सुग्रीव पर्वत' ही इस मठ का अवशेष है, यह ५०० फुट लंबा और ३०० फुट चौड़ा

गयी है,
शोक का
०० फुट
या, जहां
वास के
घम के
६५ फुट
तना ही
ु-शिखर
स्तूप की
ह्वेनसांग
बनवाया
कोई तर्क
का होने
संभवत:
ास इस
के सभी
है और
में पाया,
मिट्टी के
और भी
ईसा से
ध्या में
ष्कर्ष है
धर्म के
ता है।
ड़वाया
एक ईंट
' अक्षर
काफी
ति' की

नों को
ान व
नुसार
स्वस्थ
बौद्ध
ी हिंदू
विस्तृत
ाराम'
ीन के
र यह
न है,

क का
वशाल
ण यह
त का
होगा,
'। इस
तीन
लिए
ठ का
चौड़ा

साठ साल के बूढ़े या साठ साल के जवान?

कभी आपने गौर किया है कि सड़क पर दौड़ते यह बुज़ुर्ग ६० बरस की उम्र में भी क्यों शक्ति और स्फूर्ति से भरपूर हैं? जबकि आप अभी ३० ही के हैं फिर भी थके-थके से रहते हैं.

इसका जवाब है, केसरी जीवन.
हर दिन, दिन में दो बार दो छोटे चम्मच.

ज़ाफ़रान (केसर)–अनमोल तत्त्व!
केसरी जीवन की बोतल खोलिए. ज़ाफ़रान की लुभावनी खुशबुएँ सबसे पहले आपका स्वागत करेंगी. शुद्ध, असली ज़ाफ़रान. दुनिया की सब से महँगी जड़ी-बूटियों में से एक. जिसे ख़ास तौर से कश्मीर की वादियों से चुना गया.

केसरी जीवन में ज़ाफ़रान के अरोग्यकर और सौंदर्यवर्धक गुणों के साथ-साथ ताज़ा आँवला और कई दूसरी जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं. यह सब मिलकर आपके शरीरगठन को मज़बूत करते हैं. शरीर के टिशूज़ को वृद्धावस्था में भी चुस्त बनाए रखते हैं और आज की तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी के तनावों से आपको मुक्त रखने में आपकी मदद करते हैं. तो आज ही से इसे अपनी आदत बना लीजिए. और जीवनभर बीमारियों से मुक़ाबला करने की शक्ति जुटा लीजिए. वृद्धावस्था में सेहत का अनमोल रत्न आप भी पा लेंगे, और सारी ज़िन्दगी, ज़िन्दगी से भरपूर तरो-ताज़ा रहेगी.

झंडु केसरी जीवन

Kesari-Jivan
Kesari-Jivan

ZP/8/244 HIN

रग-रग में जान — ज़िन्दगी की शान

लीडर की प्रमाणित क्वालिटी. हमेशा से

हमेशा से, हमेशा से,

हमेशा से हमेशा से,

मेशा से,

मेशा से,

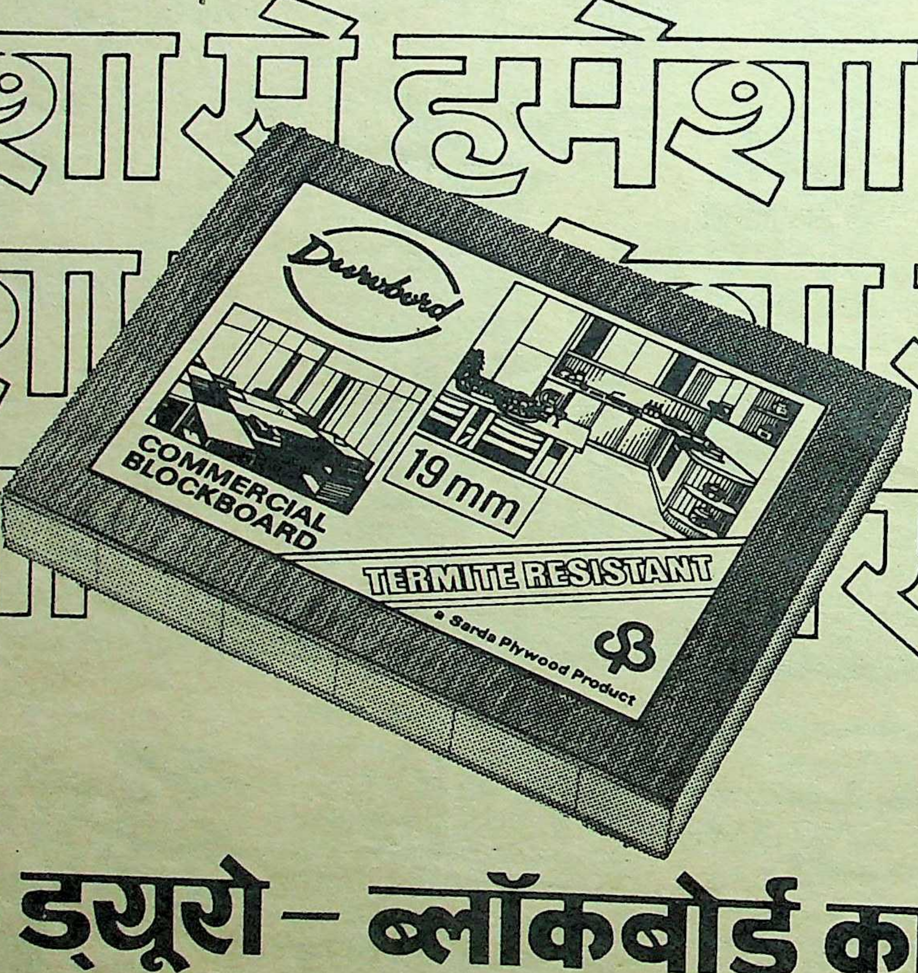
Durobord
COMMERCIAL BLOCKBOARD
19 mm
TERMITE RESISTANT
Sarda Plywood Product

यह है ड्यूरो – ब्लॉकबोर्ड का हीरो

सर्वोतम लकड़ी का उपयोग, सर्वश्रेष्ठ तकनीक व गुणवत्ता पर कठोर नियंत्रण. इसीलिए तो पिछले बीस वर्षों से ड्यूरोबोर्ड निर्विवाद रुप से सभी ब्लॉकबोर्डों में अग्रणी है. असाधारण कार्यकुशलता से बना, ज्यादा टिकने के लिए. घर घर की पसंद-ड्यूरोबोर्ड. हमेशा से, हमेशा से...

सारदा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

जैपुर (असम)

मुख्य विक्रय कार्यालय : १/७, डी. बी. गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

DPS/SPI-876

है। इसकी वृहत माप और आयतीय बनावट इस बात की पुष्टि करती है कि यह अवश्य ही एक मठ रहा होगा। इसकी भीतरी दीवार और कमरों के अवशेष जो अहाते की चारों दिशाओं को इंगित करते हैं, इस संबंध में किसी प्रकार के अन्य संदेह को एकदम निर्मूल कर देते हैं।''

कनिंघम आगे कहता है जिस अंतिम स्मारक का ह्वेनसांग ने जिक्र किया है, वहां पर बुद्ध के बाल व नाखून रखे गये थे। ह्वेनसांग के अनुसार, यह स्मारक अनेक छोटे-मोटे स्मारकों से घिरा था जो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए स्थित थे। वहां पर अनेक तालाब भी थे, जिनके पानी में पावन स्मारकों की छाया झलकती थी। उस टीले की बनावट जिस पर बाबरी मस्जिद स्थित है, उस स्तूप के वर्णन से मेल खाता है, जहां गौतम बुद्ध का बाल व नाखून रखा गया था। नगर के ठीक बीचोबीच स्थित और अनेक छोटे टीलों से घिरा यह टीला इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि यही वह स्तूप रहा होगा। बाबरी मस्जिद के पश्चिम की ओर एक नदी की परत भी दिखायी देती है। यह संभव है कि अतीत में या तो वहां एक नदी बहती रही हो या वहां पर एक बड़ा तालाब रहा हो, जिसमें मठ प्रतिबिंबित होता था। हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऐसे मामलों में सही व प्रामाणिक तथ्य पुरातात्विक अन्वेषणों या खुदाई के माध्यम से ही पता चल सकते हैं। फिलहाल, हम यह मानकर चल सकते हैं कि विवादग्रस्त मस्जिद या मंदिर एक टीले पर स्थित है और यदि हम कनिंघम व ह्वेनसांग द्वारा प्रस्तुत तर्क को मान कर चलें, तो हो सकता है कि सारे विवाद की कुंजी इस टीले में छिपी हो।

अंग्रेजों की भूमिका

इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि अवध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव की चिंगारी अंग्रेजों के प्रवेश के साथ सुलगनी शुरू हुई। १८५६ में अवध के विलय के पहले हिंदू और मुसलमान बेहद सद्भाव के साथ रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर अवध में ऐसी परंपरा थी कि कई ऊंचे खानदानों में एक भाई हिंदू रहता था, तो दूसरा इस्लाम धारण कर लेता था। इसलिए यह कोई अचंभे की बात नहीं कि अनेक ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ परिवारों ने इस्लाम को अंगीकार कर लिया था। पिछड़ी जाति के ऐसे हिंदुओं की भी संख्या कम नहीं थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, पर उनको न कुलीन (अशरफ) माना गया और न उन्होंने अरबी नाम अपनाये। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में लगान वसूलने वालों व जमींदारों के रूप में वर्चस्व हिंदुओं का ही रहा।

अवध में सांप्रदायिक संतुलन उस समय गड़बड़ाने लगा, जब राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का सवाल खड़ा किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों में पहले खूनी संघर्ष के साक्ष्य १८५३ और १८५५ के दौरान मिलते हैं। ये हेय घटनाएं उस समय हुईं जब अयोध्या के एक विशेष स्थान के संबंध में परस्पर विरोधी दावे किये गये। हनुमानगढ़ी के महंत ने दावा किया कि राम का जन्म उस जगह हुआ था, जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई है। (देखिए, 'गजेटियर आफ द प्रोविंस आफ अवध' ३ वाल्यूम, कलकत्ता—१८७७, 'डिस्ट्रिक्स गजेटियर्स आफ द यूनाइटेड प्रोविंसेज आफ आगरा ऐंड अवध, फैजाबाद, वाल्यूम ६३' एच०आर० नेविल इलाहाबाद, १९०५ और 'डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ द यूनाइटेड प्रोविंसेज आफ आगरा ऐंड अवध, बाराबंकी, वाल्यूम ६८,' एच०आर० नेविल, इलाहाबाद, १९०४)।

बाबरी मस्जिद के पश्चिम की ओर एक नदी की परत भी दिखायी देती है। यह सम्भव है कि अतीत में या तो वहां एक नदी बहती रही हो या वहां पर एक बड़ा तालाब रहा हो, जिसमें मठ प्रतिबिम्बित होता था। हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऐसे मामलों में सही व प्रामाणिक तथ्य पुरातात्विक अन्वेषणों या खुदाई के माध्यम से ही पता चल सकते हैं। फिलहाल, हम यह मानकर चल सकते हैं कि विवादग्रस्त मस्जिद या मंदिर एक टीले पर स्थित है और यदि हम कनिंघम व ह्वेनसांग द्वारा प्रस्तुत तर्क को मान कर चलें, तो हो सकता है कि सारे विवाद की कुंजी इसी टीले में छिपी हो।

यह बात स्मरणीय है कि अवध के विलय को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए लखनऊ के अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल स्लीमन ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें १८५३-५५ के सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाया गया था। कर्नल स्लीमन ने १८५४-५५ में इस सूबे का दौरा किया और उसके बाद कहा कि यहां कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गयी है। कर्नल का तर्क था कि देहात में नवाब (अवध के) का कोई प्रभाव नहीं रहा और यहां जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं रही। यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी। इसके सबूत हैं हाल के दो अध्ययन। 'द राज, द इंडियन म्यूटिनी ऐंड द किंगडम आफ अवध, १८०१-१८५९' (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९७७) में कहा गया है कि स्लीमन ने हालात का जो ब्योरा दिया था, वह सही नहीं था। 'अवध इन रिवोल्ट १८५७-१८५८: ए स्टडी आफ पापुलर रेजिस्टेंस' (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू देलही, १९८४) में आर० मुखर्जी ने यह बात प्रमाणित की है कि अंग्रेजों के प्रति आम बगावत की भावना गांवों तक पहुंच गयी थी, जिसकी परिणति १८५७-५८ के गदर में हुई। पर बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि के विवाद के कारण जो मामला भड़का, उसका अवध के विलय को जरूरी सिद्ध करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में कहा, ''विलय के कुछ पहले जो घटनाएं जिले में हुईं, उनसे साफ जाहिर होता था कि तब अराजकता फैली हुई थी। यदि सरकार का कोई असर होता, तो ऐसी घटनाएं कतई नहीं होतीं।'' (गजेटियर आफ डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद—एच०आर० नेविल) बाबरी मस्जिद-श्रीराम जन्मभूमि को लेकर जो खूनी संघर्ष हुआ, उसका विस्तृत वर्णन एच०जे० बोआस ने दिया है। (इस वर्णन की पुष्टि बाराबंकी जिले के दरयाबाद परगने में रामपुर के ताल्लुकेदार राय महादेव बाली ने की है) यह घटना १८५३ में हुई थी। इसका कारण अयोध्या की उस जमीन को लेकर महंतों और मुसलमानों में समय-समय पर होने वाले झगड़े थे, जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी है। हिंदू महंतों का तर्क था कि बाबर ने राम जन्मस्थान मंदिर को गिरा कर यहां मस्जिद बनायी थी। कहा यह भी गया कि औरंगजेब ने दूसरे मंदिरों (स्वर्गद्वार, जहां से राम ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था और त्रेता-का-ठाकुर, जहां राम ने महायज्ञ किया था) को तोड़ कर मस्जिदें बनायी हैं। लेकिन ये मस्जिदें नष्ट हो गयी थीं, इसलिए इन पर अधिकार जमाने के लिए संघर्ष करना महंतों ने वाजिब नहीं समझा। चूंकि बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के लिए विशेष पवित्र बतायी गयी थी, इसलिए बैरागियों (विष्णु के अनुयायी) तथा अन्य लोगों ने इसको तुरंत कब्जे में ले लिया। स्थिति उस समय और बिगड़ गयी, जब एक महंत को बिरादरी से निकाल दिया। वह लखनऊ पहुंचा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस महंत ने अफवाह फैलायी कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया है।

इससे भावनाएं भड़कनी शुरू हो गयीं। निकाला गया महंत मौलवी अमीर अली से मिला जो उस समय लखनऊ में था। दोनों ने कसम खायी कि वे बाबरी मस्जिद को हिंदुओं से छुड़वा कर दम लेंगे। यह महंत अयोध्या में हुए अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। मौलवी अमीर अली को लगा कि अपना सिक्का जमाने का यह अच्छा मौका है। मौलवी अमीर अली, अकबर के समकालीन अमेठी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख बंदगी मियां के वंशज थे। शेख बंदगी मियां से अकबर मिला था और उनको लगान-माफ जमीन दी थी। इसी जमीन पर अपना हक जमाने के लिए मौलवी अमीर अली लखनऊ पहुंचा था। उसने सोचा था कि बाबरी मस्जिद को आजाद करवाने के उसके प्रयासों को सुनकर नवाब प्रभावित होगा और लगान-माफ जमीन उसको मिल जायेगी।

मौलवी अमीर अली का अमेठी में अच्छा दबदबा था। वह ज्योंही अमेठी पहुंचा, उसने बाबरी मस्जिद को आजाद करवाने के लिए 'जेहाद' की घोषणा कर दी। अयोध्या के बैरागियों के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए मुसलमानों और पिछड़े हिंदुओं की सशस्त्र फौजें इकट्ठी करने में मौलवी अमीर अली समर्थ था। यह बात जब नवाब वाजिद अली शाह को पता चली, तो वह घबराया। उसने हुकुम दिया कि फैजाबाद की घटनाओं की उसको तुरंत रिपोर्ट दी जाये। लेकिन उसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसा लगता है कि फैजाबाद के अंग्रेज रेजिडेंट जेम्स ओट्रम के बढ़ते प्रभाव के कारण नवाब का असर कम हो गया था।

नवाब को चिंता हुई, उसने अमेठी के बदरुद्दौला को मौलवी अमीर अली को लखनऊ लाने के लिए कहा। नवाब वाजिद अली शाह खूनी सांप्रदायिक संघर्ष के खतरों से वाकिफ था, इसलिए उसने घोषणा की कि अयोध्या में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसने यह हुकुम भी दिया कि विवादास्पद मस्जिद इमाम को सौंप दी जाये। लेकिन नवाब के आश्वासन से मौलवी अमीर अली संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी मांग जारी रखी कि मस्जिद को तुरंत छुड़ाया जाये। उसने अपनी फौज जुटायी और बाराबंकी जिले में सफदरगंज से तीन मील उत्तर में पड़ने वाले एक गांव बांसा की ओर कूच कर दिया। बांसा में उसके साथ कुछ लोग और आ जुटे और उसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी।

मौलवी की फौज को बढ़ता देखकर नवाब वाजिद अली शाह को चिंता हुई। उसने अंग्रेज रेजिडेंट से अनुरोध किया कि अमीर अली को किसी भी तरह रोका जाये। लेकिन मौलवी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मस्जिद को तुरंत मुसलमानों को सौंपने पर ही वह रुक सकता है। इन घटनाओं के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट ने राज्यपाल की परिषद से अनुरोध किया कि वह बाबरी मस्जिद के संबंध में निर्देश जारी करे। परिषद ने रेजिडेंट को सलाह दी कि इस मामले में वह कोई पहल न करे और नवाब को पहल करने के लिए बाध्य करे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद १७६५ में हुई अंग्रेजों से शिराजुद्दौला की सहायता-संधि की शर्तों से नवाब के हाथ बंधे थे, इसलिए उसके पास पहल करने के लिए कुछ नहीं था। नतीजतन अयोध्या में यथास्थिति बनी रही। जब एक महीने के बाद तक मस्जिद बैरागियों के ही कब्जे में बनी रही, तो मौलवी अमीर अली अधीर हो उठा। वह कूच करके दरयाबाद पहुंचा और वहां बीस दिन रहा। अंग्रेजों की चुप्पी को देखकर नवाब हतप्रभ था। मौलवी को राह पर लाने के लिए नवाब ने चार 'मुफ्तियों' (फौज की टुकड़ियां) को भेजने का हुकुम दिया। नवाब की फौजों के आगमन से मौलवी के लोग भयभीत हुए और उसके दल की संख्या आधी रह गयी। बचे हुए लोग अपने नेता के साथ डटे रहे। वे अयोध्या पहुंच कर बैरागियों के मुख्य केंद्र 'हनुमान गढ़ी' को तबाह करने पर आमादा थे।

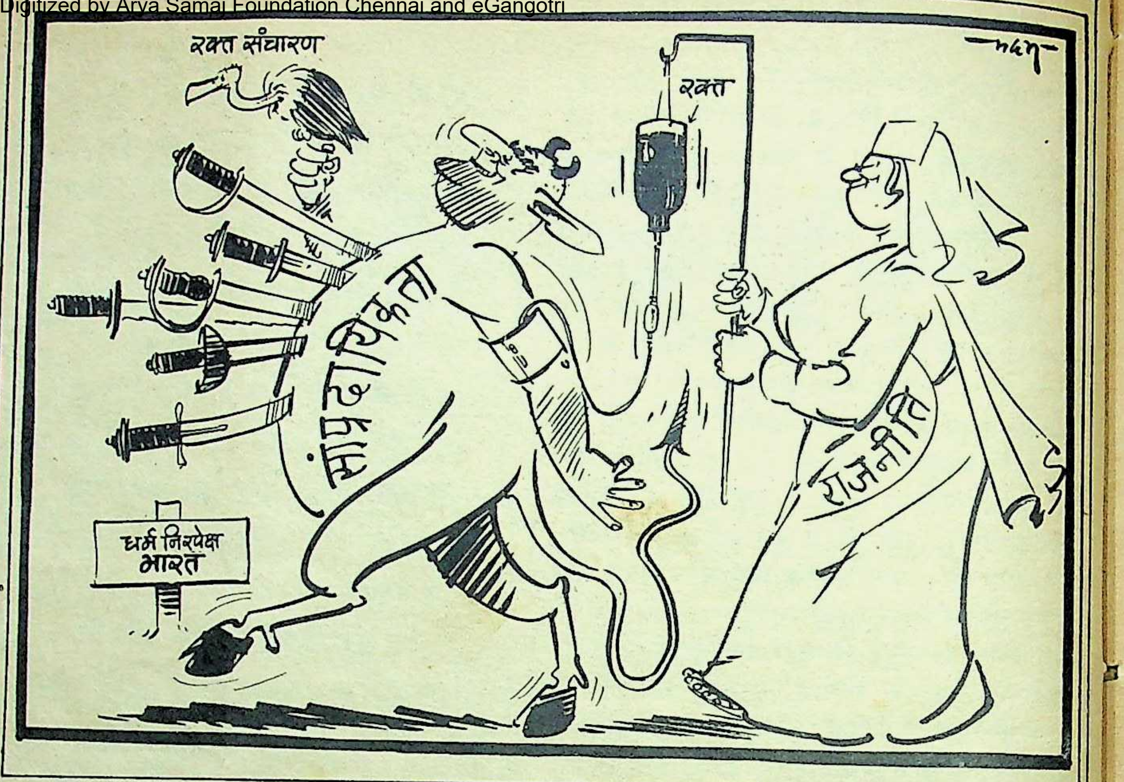

इतना तूल पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। हयात नगर के पास कर्नल बारलो के नेतृत्व में नवाब की फौजों के साथ मौलवी के लोगों की कडी भिड़ंत हुई और अंततः कर्नल बारलो के हाथों अमीर अली नमाज अदा करते समय मारा गया और उसका सिर नवाब वाजिद अली शाह के पास भिजवा दिया गया। लेकिन अमीर अली की लोकप्रियता का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि अवध के विलय के कुछ वर्ष बाद उसकी याद में रुदौली कें रहीमगंज में एक मेला लगने लगा। इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के लोग पहुंचते थे, लेकिन १९०५ तक आते-आते यह मेला लगना लगभग समाप्त हो गया था।

१८५५ में विवादास्पद स्थान को लेकर एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव हुआ। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया और हनुमानगढ़ी पर भी हमला बोला। वे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन काफी नुकसान उठाने के बाद उन्हें लौटना पड़ा। इसके बाद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर जवाबी हमला बोला। इसके बाद सरकार के हस्तक्षेप से दोनों समुदायों के वरिष्ठ लोगों ने एक समझौता किया। तय हुआ कि दोनों समुदाय के लोग उस जगह पर पूजा-नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन १८५७ के गदर के बाद अंग्रेजों ने इस समझौते में परिवर्तन कर दिया।

१८५७ के विद्रोह ने अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत कर दिया था। इसलिए अपनी रणनीति के अनुसार उन्होंने उन भारतीयों को पुरस्कृत करना उचित समझा, जिन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। जब फैजाबाद में 'विद्रोह' भड़का था, तो जमींदार तो तटस्थ रहे, लेकिन महंतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजों को शरण दी और उनको सामान मुहैया करवाया। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने भारतीय सहायकों को पुरस्कृत किया। महंतों को भी पुरस्कार मिला। उन्हें बाबरी मस्जिद के सामने की 'नजूल' (सरकारी) जमीन पर जायदादी हक दे दिया गया। राम के जन्मस्थान के महत्व को देखते हुए उन्हें बाबरी मस्जिद के सामने एक चबूतरा बनाने की भी इजाजत दे दी। इसके बाद बाबरी मस्जिद और रामजन्म स्थान पर बने चबूतरे को अलग करने के लिए एक आड़ (ग्रिल) खड़ी कर दी गयी। इस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव उभरने का जानबूझ कर मौका दिया। १८५९ के बाद मस्जिद के उत्तरी दरवाजे से केवल मुसलमान ही अंदर जा सकते थे। अंग्रेजों ने १८५५ में हुए समझौते की जान बूझकर अवहेलना की। हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को अलग-अलग दो हिस्सों में बांटने के लिए अंग्रेज क्यों प्रेरित हुए? १८५५ का समझौता ठीक चल रहा था और दोनों समुदाय खुश थे। इसके बावजूद अंग्रेजों ने मस्जिद और चबूतरे के बीच आड़ खड़ी करके दोनों समुदायों में फूट डाल दी। अंग्रेजों की नीयत पर इस बात से और भी शक हो जाता है कि बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर खड़ी है, उस पर सरकार का हक था। बाबरी मस्जिद के सामने की सारी जमीन भी 'नजूल' की थी। इसके बावजूद उन्होंने हिंदू महंतों को चबूतरा खड़ा करने के लिए उसमें से एक हिस्सा दे दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट बताते हैं कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में हिंदू पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किया।

ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेन्ट केक
ज़बरदस्त झाग। किफ़ायती धुलाई।
किफ़ायती धुलाई
A Kusum Product
Contract KP 96-86 HIN

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा
डिटर्जेन्ट केक

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

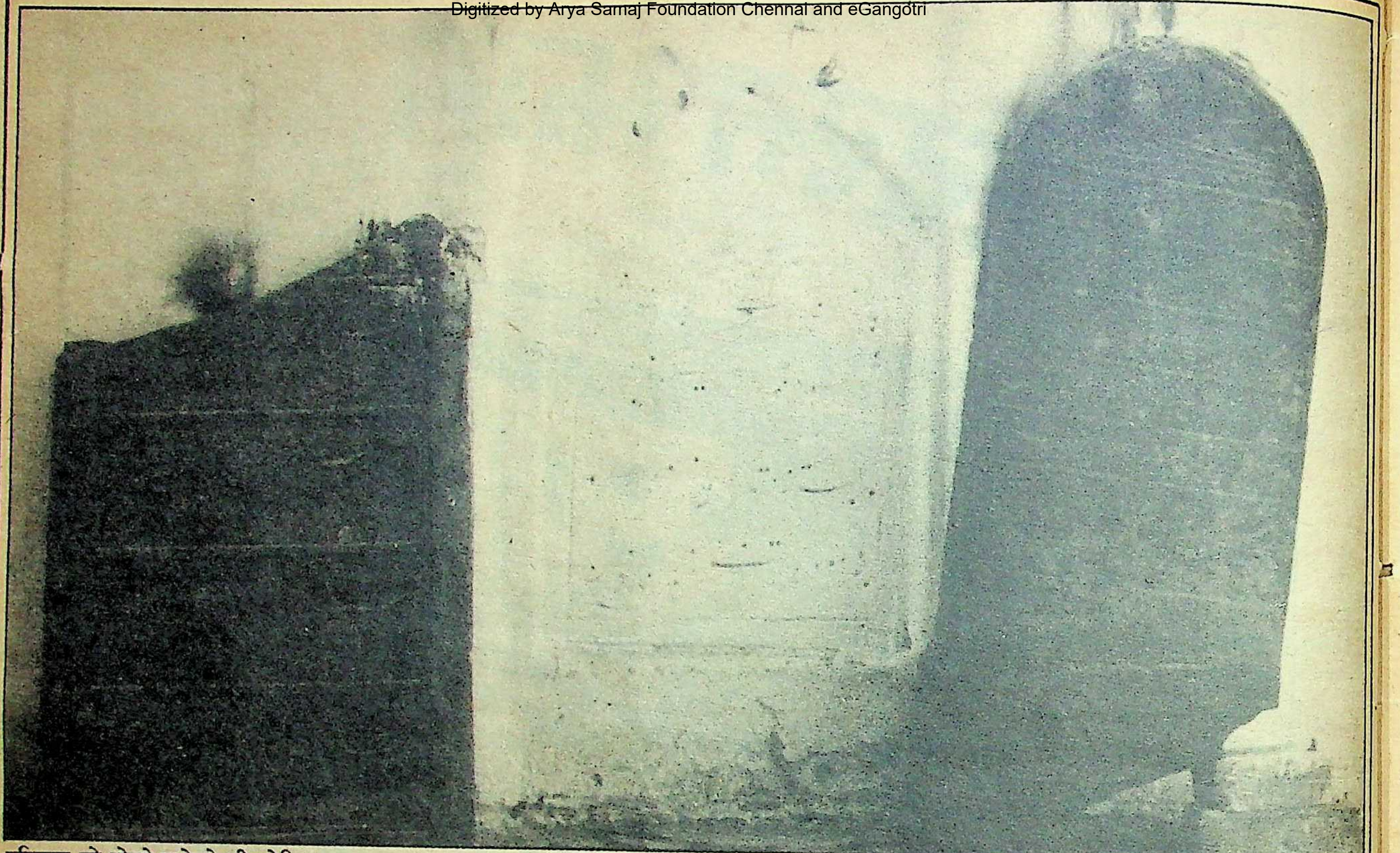

इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश

अयोध्या में हिंदू पुनरुत्थान, तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस' की लोकप्रियता के साथ बढ़ना शुरू हुआ था। १७६५ में हुई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सहायता-संधि से इसे सहायता मिली। 'तारीख-फराबख्श' के अनुसार इस संधि के बाद नवाब ने अंग्रेजों के कब्जे को ढीला करने के लिए खुले प्रयास करना शुरू कर दिये थे।

इसी के आसपास अयोध्या में हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय स्थापित और बढ़ने शुरू हो गये। १८६१ तक अयोध्या में बैरागियों के सात अखाड़े थे। इनमें 'निर्बानी' अखाड़े का आवास हनुमानगढ़ी में और 'निमोही' का आवास रामघाट और गुप्तार घाट में था। इसके अतिरिक्त 'दिगंबरी', 'खाख़ी', 'महानिर्बानी', 'संतोखी' अखाड़े थे। नवाब सिराजुद्दौला और नवाब आसफुद्दौला द्वारा इन अखाड़ों को काफी जमीनें दान में दी गयीं और अन्य सुविधाएं प्रदान की गयीं। हालत यह हो गयी थी कि १९०० ई० तक फैजाबाद जिले में फकीरों, गुसाइयों और बैरागियों की कुल मिलाकर ४७ जगहों पर भू-संपत्ति (एस्टेट) थी। इन विभिन्न संप्रदायों में 'निर्बानी' सबसे धनी माने जाते थे। इनके पास फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर में माफी की जमीनें थीं। इस संप्रदाय का हाथियों और रुपए उधार देने आदि का व्यापक व्यापार था और इसने इस आय से अनेक गांव खरीद रखे थे।

इससे साबित होता है कि नवाबों ने अयोध्या में हिंदू पुनरुत्थान को काफी बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने इसे उग्र आंदोलन मान कर बढ़ने दिया। १८१९ में अवध का मौजा (अयोध्या) अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और इसके बाद 'निमोहियों' ने विवादास्पद श्रीराम जन्मभूमि पर नियंत्रण करने के लिए सक्रिय होना शुरू कर दिया।

अंग्रेजों का दावा था कि वे असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह बात जाहिर की कि आधुनिक विज्ञान और साहित्य की शिक्षा और ईसाइयत धारण करने से भारतीयों की हालत में सुधार होगा। उन्होंने जानबूझकर प्रयास किया कि भारतीय मनीषा, साहित्य, दर्शन और इतिहास घटिया लगने लगे। इसीलिए कालिदास, कबीर, मीरा, खुसरो और गालिब जैसे कवियों का मजाक भी उड़ाया। उनको पश्चिमी कवियों के मुकाबले घटिया दिखाने की कोशिश की।

१८५३ और १८५५ के बीच हुई झड़पें हिंदू और मुसलमानों में बढ़ती उग्रता की सबूत हैं। १८५७ में हुए विद्रोह से अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि उनका भला जनता में फूट डालने में ही है। परिणामस्वरूप अंग्रेज हिंदुओं को बढ़ावा देते रहे ताकि वे बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि का दावा करते रहें। इससे साफ जाहिर होता है कि यह अंग्रेजों की रणनीति का हिस्सा था कि अपने शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए वे मुगलों की गरिमा को नष्ट करें।

अंग्रेजों का दावा था कि वे असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह बात जाहिर की कि आधुनिक विज्ञान और साहित्य की शिक्षा और ईसाइयत धारण करने से भारतीयों की हालत में सुधार होगा। उन्होंने जानबूझकर प्रयास किया कि भारतीय मनीषा, साहित्य, दर्शन और इतिहास घटिया लगने लगे। इसीलिए कालिदास, कबीर, मीरा, खुसरो और गालिब जैसे कवियों का मजाक भी उड़ाया। उनको पश्चिमी कवियों के मुकाबले घटिया दिखाने की कोशिश की। भारत की हर चीज के साथ मुगल सम्राटों की गरिमा को भी क्षीण करने की अंग्रेजों ने भरसक कोशिश की, क्योंकि वे अपने साम्राज्य की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के रास्ते में मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ी बाधा मानते थे।

अनुत्तरित सवाल

श्री सुशील श्रीवास्तव अवध के इतिहास पर कई सालों से शोधकार्य कर रहे हैं। इस शोधकार्य के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों के पुस्तकालयों, अभिलेखागारों, पुरातात्विक संग्रहालयों को खंगाला है। इस शोधकार्य के दौरान उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य आये जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद पर नयी रोशनी डालने वाले थे। राष्ट्रीय हित को देखते हुए 'माया' ने यह उचित समझा कि उनके शोध को प्रबुद्ध पाठकों के सामने रखा जाये। चूंकि कोई भी शोधकार्य नितांत परिपूर्ण और निर्दोष नहीं हो सकता, इसलिए यह शोधकार्य भी इसका अपवाद नहीं। जाहिर है इसमें भी पाठकों को कुछ खामियां नजर आयेंगी। हमारी दृष्टि में जो बड़ी खामियां हैं, उनको हम पाठकों के सामने रख रहे हैं और साथ ही अपनी स्वतंत्र खोजबीन के आधार पर इस विवाद के विषय में कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

■ सबसे पहले हम पाठकों की सुविधा के लिए अद्यतन 'यू॰पी॰ गजेटियर फैजाबाद, १९६०' के वे अंश रख रहे हैं जो अयोध्या से संबंधित हैं:

■ अयोध्या (जिसका मतलब है अजेय) महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान है। हिंदू पुराण शास्त्रों के अनुसार अयोध्या को विष्णु का ललाट माना जाता है और तीर्थ की दृष्टि से इस नगर को भारत के सात महत्वपूर्ण नगरों (सप्तपुरी) में प्रमुख माना जाता है। जैसा कि कारनेगी कहता है:

"अजुध्या का हिंदुओं के लिए वही महत्व है जो मुसलमानों के लिए मक्का का और यहूदियों के लिए यरुशलम का। ऐसा माना जाता है कि यह मरणशील धरती पर स्थापित नहीं है, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से यह स्वयं सृष्टि के महान निर्माता के सदैव अडिग रहने वाले रथ के पहिए पर अवस्थित है।" '(पी॰ कारनेगी: "ए हिस्टोरिकल स्केच आफ तहसील आफ फैजाबाद १८७०," पृष्ठ ५) इसका सबध राम के आधिवास और सूर्यवंश से है। (राम को बिष्णु के उस रूप का अवतार माना जाता है, जिसका संबंध सूर्य से है—स॰) अयोध्या अनेक शासक वंशों की राजधानी रही है। इसे वैष्णव उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। बौद्ध परंपरा में 'साकेत' नामक ऐसे स्थान का जिक्र आया है, जहां बुद्ध ने १६ वर्ष गुजारे थे। कुछ विद्वान अयोध्या और साकेत को अभिन्न मानते हैं। ५ वीं शताब्दी में यह नगर गुप्त वंश के अधीन था और उस समय वह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। शायद चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाह्यान भी अयोध्या पहुंचे थे। विभिन्न हमलावरों के कारण बार-बार तहस-नहस होने के कारण इस नगर में पुरातात्विक महत्व की चीजें नष्ट हो गयीं। ७ वीं शताब्दी के बाद यह नगर एक प्रकार से निर्जन हो गया था। मध्यकाल के शुरू में मुगल शासकों के नियंत्रण में आ जाने के कारण इस नगर का फिर से महत्व बढ़ा और यह बहुत बड़े सूबे की राजधानी बन गया था। हिंदुओं की दृष्टि से परमपवित्र नगर तो था ही। इसी कारण बाबर और औरंगजेब ने हिंदू धर्म का महत्व घटाने के लिए इसे अपवित्र किया था। १८ वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने अयोध्या के बजाय फैजाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। दरबार के हट जाने के बाद हिंदुओं पर उतना दबाव नहीं रहा, जिसके कारण अनेक मंदिर और मठ अस्तित्व में आये। शायद 'रामचरित मानस' की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसका महत्व और बढ़ता चला गया। अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय के बाद धर्म की दृष्टि से इसका विकास और हुआ। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यह स्थान हिंदुओं का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि मुसलमानो के हमले के समय यहां तीन महत्वपूर्ण मंदिर थे—जन्मस्थान मंदिर, स्वर्गद्वार और त्रेता-के-ठाकुर। ऐसा प्रतीत होता है कि १५२८ में बाबर अयोध्या आया था और उसके आदेशों से रामकोट स्थित जन्मस्थान मंदिर को तोड़ [illegible], उसकी जगह मस्जिद बनायी थी जो बाबर के नाम से जानी जाती है। मंदिर का बहुत-सा मलवा इस मस्जिद में लगाया गया, जिसमें से खंभे आज भी सुरक्षित हैं। इसी तरह औरंगजेब ने भी अयोध्या के मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता बढ़ती चली गयी। १८५५ में इस कटुता ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। परिणामस्वरूप १८५८ में मस्जिद के सामने आड़ खड़ी कर दी और हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया, जिसके कारण हिंदुओं के पास बाहरी चबूतरे पर पूजा-अर्चना करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। १९४९ के बाद स्थिति बदल गयी और हिंदू मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित करने में सफल हो गये, जिसके कारण मुकदमेबाजी का दौर शुरू हो गया जो अब भी जारी है।

इस विवादास्पद धर्मस्थल की बाहरी दीवार के बाहर 'वराह' की पुरानी और टूटी हुई प्रतिमा है। मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि वराह की प्रतिमा हरेक विष्णु मंदिर के पास होती है। आमतौर पर यह वराह अवतार का छोटा मंदिर होता है। विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में उपासना, वैष्णव धर्म की आराधना का अभिन्न अंग रहा है। इन अवतारों को विष्णु की पारंपरिक प्रतिमा में अपरिहार्य रूप से दर्शाया जाता है। यद्यपि सभी रूपों की एक जैसी लोकप्रियता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण 'वामन' और 'वराह' को माना जाता है। इनके अलग से भी मंदिर होते हैं और ये पूजे जाते हैं—जैसा कि खजुराहो तथा अन्य जगहों पर १० वीं और १४ वीं शताब्दी के बीच था। वराह को विष्णु का अवतारी रूप माना जाता है।

■ अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, इसलिए मेरी राय में यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वहां राम जन्मस्थान मंदिर अवश्य रहा होगा। अब सवाल उठता है कि क्या वह वराह की प्रतिमा अब भी वहां मौजूद है? यदि दोनों समुदायों के चुनिंदा समझदार लोग इन ऐतिहासिक साक्ष्यों की खोज करवाने का

एक सवाल हिन्दुओं से

हिन्दुओं का यह तर्क कि बाबरी मस्जिद पहले एक मंदिर था, जिसे मस्जिद का रूप दिया गया है, सरासर निराधार है। मंदिर के भग्नावशेषों को यदि किसी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है, तो उसे मंदिर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कहना , या मानना धोखे के सिवा और कुछ नहीं।

मस्जिद होने की वजह से जिस स्थान की पवित्रता भंग हो चुकी है, वह स्थान हिन्दुओं के लिए पूजा स्थल कैसे हो सकता है ? हिन्दुओं को क्या अधिकार है कि वह ऐसे स्थान पर राम और राम के परिवार तथा अन्य हिन्दू देवताओं की मूर्तियां स्थापित करें ? मस्जिद के भीतरी हिस्से के पूर्वी तरफ जबरदस्ती घुसकर बहुत ही फूहड़ ढंग से उन्होंने देवी-देवताओं के चित्रों को सजा दिया है और धर्मप्राण हिन्दुओं को धर्म के नाम पर धोखा दे रहे हैं, उनसे चढ़ावे के नाम पर व्यापार करते हैं। जो वहां का मुख्य महंत है, वह इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जबकि हिन्दू धार्मिक मान्यताएं इस तरह के कृत्यों के विरुद्ध हैं। इस तरह की हमारे यहां कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, और न ही हिन्दू धर्म शास्त्र इसकी स्वीकृति देते हैं। एक मस्जिद में राम आदि के चित्र जबरदस्ती सजाकर अबोध हिन्दुओं से पूजा करवाना क्या उचित है ? क्या यह शास्त्र सम्मत है ? क्या यह शर्म की बात नहीं है ? हिन्दू धार्मिक संगठन और उनके नेतागण जिस तरह इस संबंध में कुतर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वह उचित है ?

कोई प्रयास करें, तो सत्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लेकिन जहां इमारत का फोटो तक खींचने की अनुमति नहीं दी जाती, वहां इस तरह की खोजबीन या इमारत की सामग्री का 'कार्बन टैस्ट' जैसी बातें कैसे संभव हैं ?

■ श्री सुशील श्रीवास्तव ने अपने शोध में कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर का उल्लेख किसी धर्मशास्त्र में नहीं है।

लेकिन यह मत निराधार है, क्योंकि ऐसे प्रमाण हैं कि पहली से १० वीं शताब्दी के दौरान राम लोकप्रिय अवतार के रूप में स्थापित थे, जैसे-खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर (१० वीं शताब्दी) और गुप्त काल (५ वीं शताब्दी) में देवगढ़ मंदिर में राम स्थापित थे। (टी०ए० गोपीनाथ, एलीमेंट्स आफ हिंदू आइकोनोग्राफी वाल्यूम, भाग-१) इस संदर्भ में लगभग संपूर्ण भारत में मूर्तिशिल्प संबंधी प्रमाण मौजूद हैं। वराहमिहिर (४०० ई०) द्वारा संकलित 'बृहतसंहिता' में लिखा है कि राम की मूर्ति का गठन किस रूप में हो ? (डेवलेपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी-जे०एन० बैनर्जी, कलकत्ता, १९५४ पृष्ठ ४२०) मध्यकालीन मंदिरों में रामायण के दृश्य अंकित थे। ऐसे मंदिर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि इंडो-चाइना एवं इंडोनेशिया में भी थे। (उक्त पुस्तक: पृष्ठ ४२१)। यहां तक कि कंपूचिया (कंबोडिया, द्वितीय शताब्दी), जावा (८ वीं शताब्दी) और बोर्नियो में भी राम के मंदिर थे। ('एनशियंट इंडिया,' राधा कुमुद मुकर्जी, इलाहाबाद, १९५६)

■ राम के विभिन्न पंथों से संबंधित पत्थर और कांसे की प्रतिमाएं बाद के समय में आयी हैं। राम पहले अवतार के रूप में पूज्य थे, लेकिन ८ वीं शताब्दी के बाद उनकी भगवान के रूप में उपासना शुरू हो गयी थी। तर्पण (श्राद्ध कर्म) के समय के मंत्रों में राम का उल्लेख भी इसी बात का सबूत है। (डेवलेपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी—जे०एन० बैनर्जी, कलकत्ता, पृष्ठ ३३६)

■ यहां तक कि राम के दूत हनुमान की ९२२ ई० की एक विशाल प्रतिमा खजुराहो में मौजूद है। यह प्रतिमा सनातनी हिंदू और जैन मंदिर समूह के बीच में है और ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में यह मंदिर में रही होगी। जब राम के भक्त के मंदिर हो सकते थे, तो यह कैसे हो सकता है कि राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर न रहा होगा।

■ खजुराहो में ८४ मंदिर थे, जिनमें से विध्वंस के बाद केवल २२ रह गये हैं। जब हनुमान की वहां प्रतिमा है, तो राम के मंदिर होने की तो पूरी-पूरी संभावना है।

■ इतिहास साक्षी है कि ७वीं शताब्दी के आसपास अयोध्या नगर निर्जन हो गया था। इसके बाद मध्यकाल में राम को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा था। ऐसी स्थिति में उनका मंदिर होना आवश्यक है। हो सकता है मस्जिद में लगे खंभे उसी मंदिर के हों। शोध में उल्लिखित शकारि विक्रमादित्य की बात को 'मिथ' माना जा सकता है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ८ से १० वीं शताब्दी तक अयोध्या के क्षेत्र पर गुर्जर परिहारों का शासन था। इसके बाद ११ वीं शताब्दी में जयचंद का शासन था (जौनपुर शिलालेख)। जयचंद इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसका तो कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं कि वह राम जन्म मंदिर किसने बनवाया था, जिसके खंभे मस्जिद में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यह संभव है कि उपर्युक्त दोनों शासकों में से किसी ने यह मंदिर बनवाया होगा। श्रीवास्तव भी मानते हैं कि खंभे इसी समय के हैं। यह भी संभव है कि मंदिर जनता के दान से बना हो क्योंकि अयोध्या में जैन और बौद्ध मंदिर हैं, जबकि वहां किसी जैन या बौद्ध राजा का शासन नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि खजुराहो और वाराणसी में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मों के शक्तिशाली केंद्र रहे हैं तथा सभी एक साथ फलते-फूलते रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अयोध्या में बौद्ध स्तूप हो सकता है और राम मंदिर नहीं हो सकता, कुछ जमता नहीं।

■ जहां श्रीवास्तव विक्रमादित्य की बातें करते हैं, वहां यह नहीं स्पष्ट होता कि वह कौन-सा विक्रमादित्य था? कालिदास ने जिस विक्रमादित्य का वर्णन किया है, वह या कि मौर्य और गुप्तकालीन विक्रमादित्य ? लगता है विक्रमादित्य एक उपाधि थी नाम नहीं और यह स्वर्णकालीन मौर्य या गुप्त काल का कोई राजा रहा होगा।

■ यदि 'अयोध्या माहात्म्य' १८ वीं शताब्दी की कृति है, तो इसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं ? श्रीवास्तव ने 'अयोध्या माहात्म्य' के आधार पर माप-जोख से यह सिद्ध किया है कि ठीक बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मस्थान नहीं हो सकता, २०-२५ गज इधर-उधर रहा होगा, लेकिन यह माप-जोख बिलकुल सही-सही कैसे हो सकती है ?

■ श्रीवास्तव का मत है कि अंग्रेजों ने यह प्रचार करने के लिए कि बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि की जगह बनी है, लेडन (बाबरनामा) के उल्लेखों का सहारा लिया है। लेकिन लेडन ने तो कहीं यह नहीं लिखा कि बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ा था। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि यह विवाद अंग्रेजों ने भड़काया ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर इक्तिदार आलम खान के अनुसार इस विवाद में अंग्रेजों का बहुत कम हाथ रहा है।

■ यह बात तार्किक नहीं लगती कि 'बाबरनामा' में जन्ममंदिर तोड़ने का कोई जिक्र होना चाहिए था। जिसने मंदिर तोड़ा है, क्या वह उसका जिक्र करेगा ? मंदिर तोड़ने वाले क्या किसी अन्य शासक ने तोडे गये मंदिरों का जिक्र किया है ?

■ सिर्वा और घाघरा के जिस संगम पर बाबर के पड़ाव डालने का जिक्र है, उसको ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत संभव है कि इन नदियों ने कालांतर में अपना बहाव बदल दिया हो।

■ जब बाबर अयोध्या के करीब था, तो इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं पहुंचा ?

■ जब बाबर का पूरा समय लड़ाई में गुजर रहा था, ऐसे समय में यह कैसे संभव था कि वह दिल्ली या अन्य जगहों से कारीगर बुला पाता।

■ श्रीवास्तव ने मस्जिद के बाहर की इबारत पर संदेह किया है, लेकिन अंदर की इबारत पर नहीं।

■ श्रीवास्तव का कथन है कि बाबर निष्ठावान मुसलमान था, लेकिन प्रो० खान का कहना है, "बाबर धर्म के प्रति बहुत उदासीन था।" अगर यह सही है, तो यह तर्क निराधार है कि बाबर जैसा व्यक्ति विवादास्पद जगह पर मस्जिद बनाने का आदेश नहीं दे सकता था।

यहां तक तो शोध की बात हुई, अब अन्यत्र प्रकाशित बातों के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा:

■ यत्र-तत्र यह छपा है कि अंग्रेज इतिहास लेखक कनिंघम ने 'लखनऊ गजेटियर' में लिखा है कि हिंदुओं ने इस मस्जिद के निर्माण के समय अपनी जान की बाजी लगा दी थी और एक लाख चौहत्तर हिंदू मारे गये थे, लेकिन ऐसा कोई 'लखनऊ गजेटियर' नहीं है और न ही कनिंघम ने कभी कोई गजेटियर लिखा है। हां, नकली साहित्य जैसे—'रक्त रंजित इतिहास' में यह बात अवश्य आयी है। वैसे नेविल ने अपनी पुस्तक 'फैजाबाद ए गजेटियर', वाल्यूम ४२ के पृष्ठ १७८ पर पूरे अवध की जनसंख्या कुल ९ हजार ९ सौ ४९ दी है जो कि १८८१ तक ११ हजार ६ सौ ४३ हो गयी थी। जाहिर है जिस समय के खूनी संघर्ष की बात कही जा रही है, उस समय तो जनसंख्या और भी कम रही होगी।

■ यह भी कहा जाता है कि 'सुलतानपुर गजेटियर' के पृष्ठ २६ पर कर्नल मार्टिन की एक रिपोर्ट छपी है। लेकिन यह कौन-सा गजेटियर है, इसको काफी ढूंढ़ने पर भी कोई पता नहीं चला। जो मिला उसमें कहीं मार्टिन की रिपोर्ट नहीं थी।

■ इसी तरह 'माडर्न रिव्यू' के ६ जुलाई, १९२४ के अंक की भी बात की जाती है, जिसमें स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के नाम से छपे विवरण का उल्लेख बताया जाता है। इस उल्लेख में बाबर द्वारा राम जन्मभूमि तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के शाही फरमान का जिक्र है। यहां केवल इतना ही कहना है कि 'माडर्न रिव्यू' का '६ जुलाई' जैसा कोई अंक नहीं हो सकता। 'रिव्यू' मासिक था और इलाहाबाद से रामानंद चट्टोपाध्याय द्वारा मुद्रित और संपादित था।

■ कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद में झरोखे हैं जो मस्जिदों में नहीं होते। लेकिन इन 'झरोखों' को ठीक झरोखा नहीं कहा जा सकता, हां झरोखे जैसे ये लगते जरूर हैं। लेकिन यह हिंदू स्थापत्य का प्रभाव माना जा सकता है। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मस्जिद नहीं है।

■ हिंदू प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि इस मस्जिद में लकड़ी का प्रयोग हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह बात प्रामाणिक नहीं। शर्की शैली की मस्जिदों में लकड़ी का प्रयोग हुआ है। मेहराब इन मस्जिदों में लट्ठे पर ही टिकी हैं।

■ हिंदू पक्षधर यह भी तर्क देते हैं कि शेरों की मूर्तियां मस्जिद के द्वार पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अन्यत्र भी ये मूर्तियां हैं।

■ यह भी तर्क दिया जाता है कि मस्जिद में मीनारें होना जरूरी हैं, जहां से मौलवी अजान देते हैं। अजान के लिए इनका उपयोग होता हो या न होता हो, लेकिन ये मस्जिद का एक प्रतीक अवश्य होती हैं और मस्जिद के भवन से ही ऊपर निकली होती हैं।— 'इनसाइकिलोपीडिया अमेरिकाना' के अनुसार मीनारों का प्रयोग मस्जिदों में ६७३ ई० से होने लगा है और ये मस्जिद का अपरिहार्य अंग मानी जाती हैं। इसलिए यह बात आश्चर्यजनक है कि इस मस्जिद में मीनारें क्यों नहीं?

■ इस मस्जिद में परिक्रमा के होने को भी आश्चर्यजनक माना जाता है, लेकिन इसे ठीक परिक्रमा नहीं बताया जा सकता। हां, परिधि में छूटा स्थान परिक्रमा जैसा प्रतीत अवश्य होता है।

■ इसमें कोई शक नहीं कि राम जन्मभूमि मंदिर के पक्षधरों द्वारा नकली इतिहास गढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में हिंदू अकेले नहीं। बाबरी मस्जिद के पक्षधर भी यह काम कर रहे हैं। 'तवारीखे अवध' (कमालुद्दीन हैदर १८८५) में कहा है कि 'हनुमानगढ़ी' की जगह मस्जिद थी, जिसके दरवाजे नहीं थे। कोई बैरागी आया और धूनी जमाकर पहले मूर्ति स्थापित की और फिर यहां मंदिर बनवाया। इस दस्तावेज की कोई ऐतिहासिक मान्यता नहीं है। इसी तरह के और भी सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

■ इस ऐतिहासिक तथ्य पर किसी ने गौर नहीं किया है कि मुस्लिम शासकों ने मस्जिदें भी तोड़ी हैं। इसका उदाहरण है दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा १५वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के शर्की राजाओ द्वारा बनायी मस्जिदों और स्मारकों का तोड़ा जाना। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुस्लिम शासकों ने केवल किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा के कारण धर्मस्थानों और इमारतों को नहीं तोड़ा, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने पूर्व शासकों की महिमा को नष्ट करना था। (पर्सी ब्राउन की इंडियन आर्किटेक्चर—इस्लामिक पीरियड—पृष्ठ ४२)

■ अभिलेख साक्षी हैं कि मस्जिदों के निर्माण में हिंदू कारीगरों का इस्तेमाल हुआ है। महमूद शाह (१४३६ से ५८ तक) की रानी बीबी राजा ने १४५० में लाल दरवाजा मस्जिद बनवायी, जिसका आर्किटेक्ट हिंदू था, जिसका नाम था कमांऊ।

■ मुगल शासन के प्रारंभिक काल में देश इतना अस्त-व्यस्त था कि कोई विशिष्ट वास्तुकला की इमारत बनाना संभव नहीं था। १५२६ में बाबर ने दो मस्जिदें बनवायी थीं—काबली बाग, पानीपत में और जामी मस्जिद संभल में। इनके बारे में बाबर ने अपने संस्मरण (बाबरनामा वाल्यूम—२ पृष्ठ ५३) में कहा है कि ये अच्छी नहीं बनी हैं। इससे लगता है कि बाबर वास्तुकला के सौंदर्य से अवगत था, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला, जिससे लगे कि बाबर हिंदू धर्म स्थलों की वास्तुकला का प्रशंसक था। हां, ऐसे सबूत हैं कि बाबर गैरधार्मिक इमारतों का प्रशंसक था। मसलन ग्वालियर के दुर्ग में बने महल की बाबर ने (१५२८ में) प्रशंसा की है। (आर्स्किन द्वारा अनूदित 'बाबर्स मेमोएर्स', पृष्ठ ३४६)

■ यह कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़ कर, उनकी जगह मस्जिदें नहीं बनवायीं। इसका एक उदाहरण है जौनपुर की 'अटाला मस्जिद'। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस मस्जिद की जगह 'अटल देवी' का मंदिर था। इस मंदिर तथा अन्य आसपास के मंदिरों के मलबे से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। (पर्सी ब्राउन कृत 'इंडियन आर्किटेक्चर—इस्लामिक पीरियड'—पृष्ठ ४२)

■ इतिहास को न नकारा जाता है न ऐतिहासिक तथ्यों को पलटा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन बाबर या लोदी ने जो कुछ किया है, वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए आज के संदर्भ में अर्थहीन है। किसी भी ब्रिटिश स्मारक को तोड़ने की मांग, आज हम केवल इस आधार पर नहीं कर सकते, कि अंग्रेज हमारे उत्पीड़क थे। हम यह मांग नहीं कर सकते कि जिस जगह पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर लटकाये गये थे, वहां मंदिर बनाये जायें। इस तरह की मांगें तर्कसंगत नहीं कही जा सकतीं। वैसे चाहे राम का मंदिर राम के जन्मस्थल के ऊपर बने या वहां से १० गज या १० मील हटकर बने, इससे मंदिर की पवित्रता या ऐतिहासिकता पर कोई असर नहीं पड़ता। ईश्वर तो सर्वव्यापी है और भक्ति का स्थान मन में होता है। जो धर्मांध मंदिर बनाना चाहते हैं, वे 'मनमंदिर' क्यों नहीं बनाते। राम के लिए वही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है।

एक सवाल मुसलमानों से

बाबरी मस्जिद की संरचना को देखते हुए मौजूदा स्थिति में किसी भी हालत में इसे मंदिर नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इसमें कुछ हिन्दू मंदिरों जैसे लक्षण-मेहराबदार ताख, जिसे अंग्रेजी में अलकव कहते हैं तथा हिन्दू मंदिरों के भग्नावशेष, जैसे लिटल (उत्तरंग, द्वाराग्र काष्ठ) और विशेषकर कसौटी पत्थर के चौदह खंभे आदि हैं। यह खंभे निश्चित रूप से किसी हिन्दू मंदिर के हैं, क्योंकि इनमें हिन्दू कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। इन खंभों को ध्यान से देखने पर लगता है कि इन से मानव आकृतियों को मिटा दिया गया है, या मिटाने की कोशिश की गयी है। लेकिन आश्चर्य है कि किसी ने भी सूक्ष्मता से इसका परीक्षण नहीं किया। लेकिन अपने व्यक्तिगत परीक्षणों से मैंने पाया कि घुसते समय दाहिनी ओर जो पहला खंभा है, उसके निचले भाग में हनुमान की एक बहुत ही सुंदर आकृति खुदी हुई है, जो स्पष्ट देखी जा सकती है।

प्रस्तुत लेख में जिस वाराह की चर्चा हमने की है, वह भी वहां मौजूद है। यह मूर्ति दक्षिण पूर्व में पीपल और नीम के पेड़ के नीचे और दीवार में जड़ी हुई है। इसलिए मस्जिद की पवित्रता भी इससे संदिग्ध लगने लगती है। इसलिए मैं मुस्लिम धर्मावलंबियों से पूछना चाहता हूं कि कथित बाबरी मस्जिद नमाज अदा करने के लिए क्या कभी पवित्र स्थान था, या आज है?

■ बहुत से लोगों को यह भ्रांति है कि 'रामचरितमानस' के बाद राम लोकप्रिय हुए और उनके मंदिर बने। शहाबुद्दीन साहब (देखिए साक्षात्कार) भी यह बात कहते हैं। लेकिन हम ऊपर प्रतिपादित कर चुके हैं कि राम की महिमा, मूर्तियां और मंदिर कब से हैं और उनके कितने पुराने मंदिर रहे हैं।

इन सब बातों को मद्दे नजर रख कर न तो दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर नहीं था और न यह कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवायी। जब तक इमारत की 'कार्बन डेटिंग' नहीं होती— खासतौर से उन खंभों की, तब तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण देना संभव नहीं है। 'सेंटर आफ एडवांस स्टडी इन हिस्ट्री' के निदेशक और 'इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च' के अध्यक्ष प्रो० इरफान हबीब की इस बात में मैं भी यकीन रखता हूं कि जिस तरह का व्यवहार दोनों पक्ष के लोग कर रहे हैं, उससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमारे सामने बड़ा सवाल यही है कि हम आधुनिक वैज्ञानिक नजरिये को अपनायें या १६वीं शताब्दी की ओर लौटें?

—[illegible]

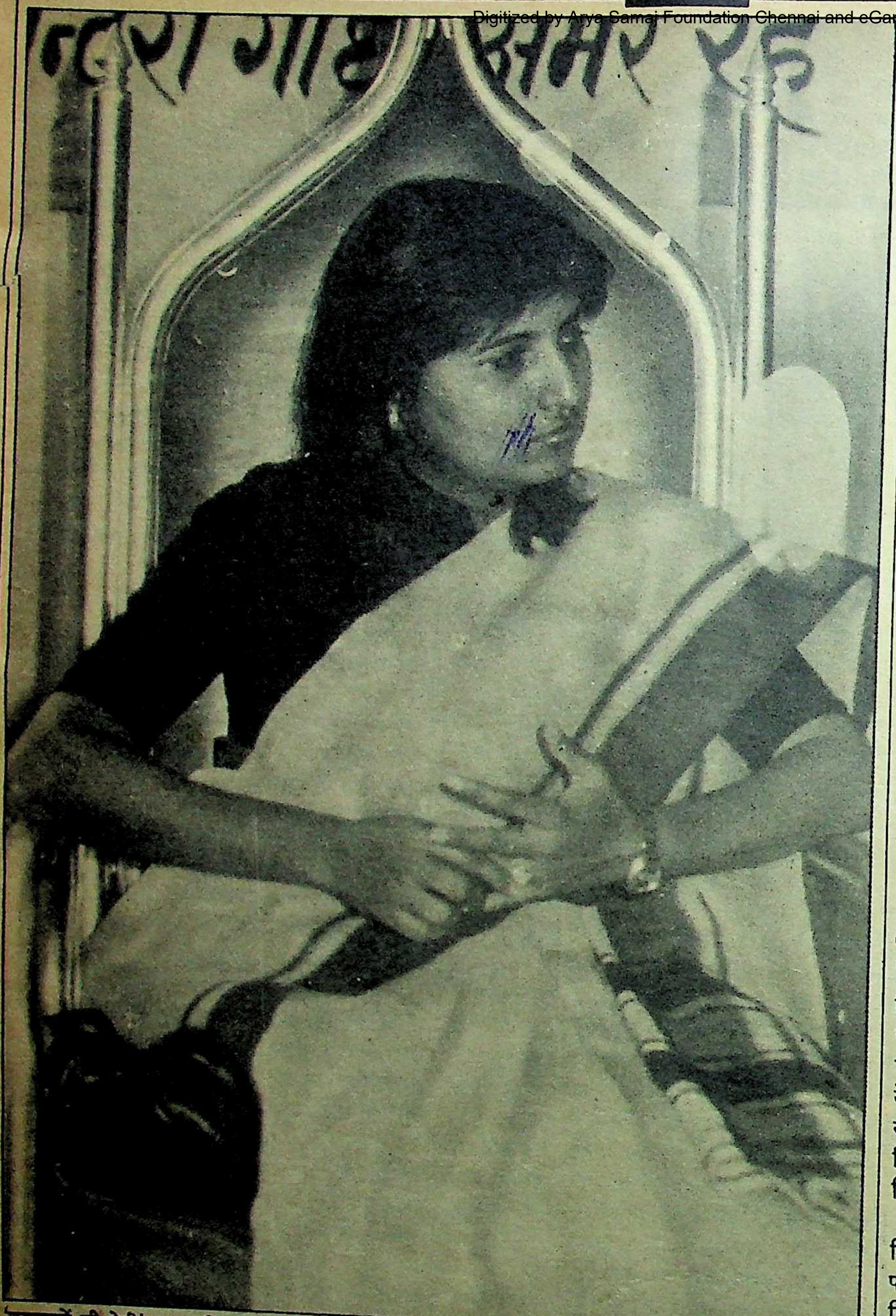

'तबादलों की देवी' : डा० विजयलक्ष्मी साधो

नेता
सुभाष जी
यादव
वोर्म

बाप तो बाप, लेकिन बेटी भी !

हरिजन नेता सीताराम साधो १९५२ से १९८५ तक मध्य प्रदेश विधानसभा में महेश्वर (खरगौन) का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन १९८५ में उनकी पुत्री डा० विजयलक्ष्मी उनकी उत्तराधिकारी बन गयीं और पिता मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम के अध्यक्ष बन गये। पिता-पुत्री दोनों की ऐसी कौन-सी गतिविधियां हैं कि जिनकी शिकायतें प्रधानमंत्री तक पहुंची हैं?

हरिजन नेता और म०प्र० चर्म विकास निगम के वर्तमान चेयरमैन सीताराम साधो ने पश्चिम निमाड़ में महेश्वर से पहला चुनाव १९५२ में लड़ा था और १९८५ तक लगातार वह विधायक बने रहे। १९८५ में उन्होंने अपना उत्तराधिकार अपनी बेटी डा० विजयलक्ष्मी साधो को सौंप दिया। डा० साधो आज विधायक हैं और अपने पहले ही विधायक-काल में अपने आचरण के कारण पर्याप्त विवादास्पद हो गयी हैं।

यह अकारण नहीं है कि पिता-पुत्री के खिलाफ उनके क्षेत्र में असंतोष दिनोदिन तेज़ी से पनपता जा रहा है। हालत यह हो गयी है कि पिछले दिनों क्षेत्रीय नागरिकों ने डाक-बंगले में पिता-पुत्री का घेराव किया और नवंबर के शुरू में क्षेत्रीय सांसद सुभाष यादव जब दौरे पर आये, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने डा० साधो और उनके पिता की ढेरों शिकायतें कीं। आरोपों और शिकायतों की बौछार इतनी तीखी थी कि पिता ने अपने एवं अपनी पुत्री के आचरण व क्रियाकलापों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह कार्यकर्ताओं का असंतोष ही है जिसके कारण विधायक ने सूखे की भयावह विभीषिका के बावजूद अपने इलाके का दौरा नहीं किया और पूर्व-सूचना के बावजूद मंडलेश्वर में उस बैठक में भाग नही लिया जो सांसद सुभाष यादव ने सूखे व राहत कार्यों पर विचार के लिए बुलायी थी।

तबादला उद्योग: मध्यप्रदेश में अनेक कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के अनिश्चित चरित्र और ज्वार-भाटे की संभावना को देखते हुए स्वर्णिम भविष्य के लिए बंधु-बांधवों के नाम से फैक्ट्रियां चालू कर दी हैं। साधो व उनकी पुत्री ने किसी कारखाने की स्थापना तो नहीं की, लेकिन तबादला उद्योग को अवश्य अंगीकार कर लिया है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि पिता-पुत्री के राजनीतिक प्रभामंडल के तले तबादला उद्योग फल-फूल रहा है और पिता-पुत्री अपने रुतबे के हंसिये से चांदी काट रहे हैं।

खरगौन जिला २० सूत्री कमेटी के सदस्य चंद्रकांत पाटीदार, जिला पंचायत के सभापति सिंगदार पंटेल, ऊन जिला ग्रामीण कांग्रेस-इ के अध्यक्ष जगदीश पाटीदार और ऊन ब्लाक कांग्रेस-इ के प्रशिक्षक नरेंद्र सिह मंडलोई ने गत दिनों प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पत्र लिखकर पिता-पुत्री के कारनामों की शिकायत की। पत्र में पिता-पुत्री को 'सत्ता का दलाल' निरूपित करते हुए कहा गया है कि वे क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों व असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं और तबादलों के धंधे में लिप्त हैं। पत्र में एक दृष्टांत का भी उल्लेख है: बैंक आफ इंडिया की ऊन शाखा के प्रबंधक ओ०पी० जाली के ऋण प्रकरणों व आई०आर०डी०पी० योजना में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच की मांग उक्त चारों नेताओं ने की थी। क्षेत्रीय सांसद सुभाष यादव व विधायक चिड़ाभाई डाबर ने भी बैंक के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर जाली का तबादला अन्यत्र कर दिया गया, मगर जाली अन्यत्र जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने दौड़-धूप की और अंततः डा० साधो के जरिये वह अपना तबादला निरस्त कराने में सफल रहे। प्रधानमंत्री को भेजे कथित पत्र में पिता-पुत्री के बारे में लिखा है, "ये दोनों सत्ता के दलाल हैं और अपने आप को मोतीलाल वोरा का नजदीकी बताकर अधिकारियों पर दबाव डालकर गैर-कानूनी काम करवाते हैं और नहीं करने पर स्थानांतरण की धौंस देते हैं।"

मध्य प्रदेश में अनेक कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के अनिश्चित चरित्र और ज्वार-भाटे की संभावना को देखते हुए स्वर्णिम भविष्य के लिए बंधु-बांधवों के नाम से फैक्ट्रियां चालू कर दी हैं।

खरगौन जिले में महेश्वर के थाना प्रभारी रामेश्वर सविता का स्थानांतरण चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ताओं व अखबारी रिपोर्टों के अनुसार पिता-पुत्री ने सविता का तबादला इसलिए करवाया, क्योंकि वह इलाके के सटोरियों को प्रश्रय नहीं दे रहा था। आम चर्चा है कि सविता के तबादले के लिए सटोरियों ने अच्छी खासी रकम खर्च की। इसी क्रम में बताते हैं कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निगम और सिविल सर्जन डा० विश्नारं समेत अनेक चिकित्सकों का तबादला भी पिता-पुत्री ने निरस्त कराया। खरगौन के पत्रकार-द्वय उमेश गोस्वामी व संजय शर्मा से जब इस सिलसिले में चर्चा हुई, तो उन्होंने उक्त प्रकरणों की पुष्टि की और कहा कि डा० साधो को इस क्षेत्र में 'तबादलों की देवी विजयलक्ष्मी' के नाम से जाना जाने लगा है। पत्रकार-द्वय ने यह भी बताया कि क्षेत्र के अन्य नेताओं के विपरीत विजयलक्ष्मी साधो पत्रकारों से मिलने से कतराती हैं और अगर मिलीं तो पत्रकारों से उनका सलूक अच्छा नहीं होता। बहरहाल, जून, '८७ में खरगौन में डा० साधो ने पत्रकारों से कहा था कि यदि वे तबादलों का एक भी प्रकरण बता देंगे, तो वह इस्तीफा दे देंगी। पत्रकारों के बदले उनकी इस चुनौती का उत्तर महेश्वर के हरिजन कार्यकर्ताओं ने १५८ तबादलों का हवाला देकर दिया। ब्लाक कांग्रेस-इ कमेटी ने बाकायदा निंदा प्रस्ताव पारित कर चेतावनी दी कि यदि पिता-पुत्री आगे तबादलों के फेर में पड़े, तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जायेगी।

टकराव: कमेटी की चेतावनी, प्रधानमंत्री से शिकायत और बदनामी से पिता-पुत्री कितना चेतते हैं, यह आनेवाला कल बतायेगा, लेकिन इसमें शक नहीं कि पिता-पुत्री के हौसले बुलंद हैं। पिता जहां चर्म विकास निगम के अध्यक्ष पद पर डटे हुए उसे चूना लगा रहे हैं, (देखिये बाक्स) वहीं डा० साधो मंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। भोपाल-दरबार के कतिपय आकाओं का वरदहस्त उन्हें प्राप्त है। स्थानीय नेताओं में केवल मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के भूतपूर्व चेयरमैन और प्रकाशचंद सेठी के विश्वासपात्र अमोलकचंद छाजेड़ का सक्रिय सहयोग व समर्थन ही उन्हें प्राप्त है। खरगौन की दसों सीटों पर कांग्रेस काबिज है, लेकिन दस विधायकों में केवल एक उमराव सिह फाटला आधे-अधूरे मन से उनके साथ हैं, अन्यथा सारे-के-सारे विधायक व स्थानीय नेता खरगौन के सांसद व सहकारिता के बेताज बादशाह सुभाष यादव के साथ हैं। शक्ति और सामर्थ्य को तौलें, तो बात अजीब लगती है मगर सच यह है कि साधो यादव से टकराव के रास्ते पर चल रही हैं।

सांसद व विधायक में टकराव का सार्वजनिक

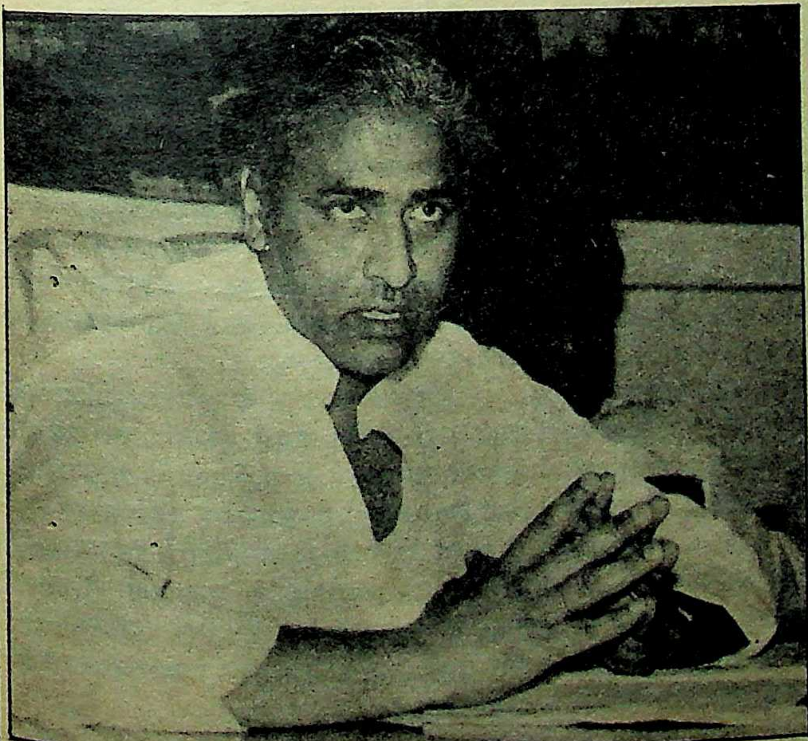

पिता-पुत्री से टकराव: सुभाष यादव

हरिजन छात्रावास की दुर्गति

सफेद हाथी का निरंकुश महावत

मध्यप्रदेश में कार्यरत दर्जनों निगमों में इने-गिने निगमों को छोड़ दें, तो अधिकांश सरकारी निगम सफेद हाथी ही सिद्ध हुए हैं। ऐसा ही एक निगम है मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक सीताराम साधो। इस निगम की स्थापना २५ नवंबर, १९८१ को इस प्रावधान के साथ हुई थी कि इसका मुख्यालय भोपाल रहेगा। साधो को निगम के गठन के कुछ माह बाद ही अध्यक्ष बना दिया गया था और तब से वह इस पद पर आसीन हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने जिस प्रकार स्वच्छंद आचरण किया है, उसके आधार पर उन्हें सफेद हाथी के निरंकुश महावत की संज्ञा दी जाये, तो बेजा न होगा।

साधोजी की मनमरजी का पहला उदाहरण तब मिला, जब उन्होंने निगम का मुख्यालय मंडलेश्वर में बनाने का फैसला किया। इससे उन्हें दोहरा लाभ यह हुआ कि एक तो वह भोपाल में अपने बंगले में रह कर दैनिक भत्ता लेते रहे, दूसरी ओर मंडलेश्वर-भोपाल के बीच यात्रा कर सरकारी पैसा फूंकते रहे। १ अक्तूबर, १९८२ से मार्च, १९८४ के बीच उन्होंने निगम के वाहन से १३८९० किमी० यात्रा की और पेट्रोल पर १६२०५ रुपए की रकम व्यय की। इस दौरान उन्होंने ५१ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, २५० दिनों का भत्ता करीब १२ हजार रुपए निगम से वसूल किया। निगम के अध्यक्षों को प्रदत्त सामान्य सुविधाओं के अंतर्गत अध्यक्ष को दो अर्दलियों की सेवाएं मिलती हैं, लेकिन साधोजी के यहां तीन अर्दली चाकरी में लगे रहे। तीसरे यानी अतिरिक्त अर्दली को निगम के कोष से नवंबर, १९८२ से फरवरी, १९८५ के मध्य ८८२० रुपए का भुगतान किया गया। साधोजी ने निगम का मुख्यालय १९८२ में बगैर किसी से पूछेताछे मंडलेश्वर किया था और करीब डेढ़ साल बाद उन्होंने पुनः किसी से पूछेताछे ही निगम का मुख्यालय मंडलेश्वर से उठाकर भोपाल कर दिया।

निगम के संचालक मंडल ने २६ नवंबर, १९८२ को अपनी चौथी बैठक में तय किया कि अध्यक्ष को एक कार मय चालक के उपलब्ध की जाये। जाहिर है कि साधोजी को कार मय ड्राइवर के मिली, लेकिन वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। ३० जुलाई, १९८३ को भोपाल मोटर्स, सुल्तानिया रोड, भोपाल से एक जीप एक लाख चार हजार रुपए में खरीदी गयी और यह जीप (एम बी सी २६२), अम्बेसडर कार (एम बी सी ९) के साथ तब से उनकी और उनके परिजनों की सेवा में लगी हुई है। फरवरी, १९८५ तक इस जीप के रखरखाव पर करीब २० हजार रुपए और इस दरम्यान चालक के वेतन पर १० हजार रुपए खर्च हो चुके थे।

साधोजी के पास गाड़ियां भले ही दो हों, किंतु उनके क्षेत्र के लोगों की यह आम शिकायत है कि उनकी बिटिया विजयलक्ष्मी साधो क्षेत्र व क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं लेतीं। यह सच है कि पूरा साधो परिवार मंडलेश्वर छोड़कर भोपाल में बस गया है और डा० साधो का अधिकांश समय भोपाल में या फिर दिल्ली में बीतता है। रही बात उनके पिता सीताराम साधो की सो चर्म विकास निगम उपलब्धियों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। जानकार सूत्रों के अनुसार चेयरमैन साहब एक सहायक प्रबंधक के चंगुल में हैं और उसकी हर बात पर मोहर लगा देते हैं। ऐसे में निगम की दुर्गति न हो, तो यह आठवां आश्चर्य ही होगा।

—सुधीर सक्सेना

तौर पर खुलासा तब हुआ था, जब मोहन गुप्ता खरगौन में कलेक्टर थे। मोहन गुप्ता के काल में पत्रकारों ने राहत कार्यों के गेहूं की तस्करी और बाजार में बिक्री का भंडाफोड़ किया और विधायक करुणा दांगी और सुभाष यादव ने मामले को अलग-अलग स्तरों पर उठाया। इस मामले को लेकर कलेक्टर मोहन गुप्ता व सांसद यादव में खुला टकराव हुआ। इस टकराव के दरम्यान जन प्रतिनिधियों में केवल डा० साधो ने ही मोहन गुप्ता का साथ दिया। बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष मोहन गुप्ता की जमकर पैरवी भी की, लेकिन अंततोगत्वा इस टकराव में जीत सुभाष यादव और उनके सहयोगी विधायकों की हुई और कलेक्टर मोहन गुप्ता को खरगौन छोड़कर भोपाल में पंचायत और समाज कल्याण विभाग की बागडोर संभालनी पड़ी। हां, इस मामले में यह अवश्य उजागर हो गया कि कुछ प्रमुख अधिकारियों का सहयोग साधो को प्राप्त है। जहां तक पश्चिम निमाड़ में सुभाष यादव की छवि और लोकप्रियता का प्रश्न है, वह भी विवादों से परे नहीं रहे हैं, किंतु खरगौन में ११ करोड़ रुपए की लागत से सहकारी सूत मिल की स्थापना के उपक्रम ने उनके पांव इलाके में जमा दिये हैं। पश्चिम निमाड़ के खेतों में नर्मदा का जल पहुंचाने और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष के नाते किसानों को फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ पहुचाने के कारण उनकी किसानों में लोकप्रियता व पैठ में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों सुभाष यादव ने खरगौन में सूखे व राहत कार्यों पर विचार के लिए बैठक बुलायी, तो उसमें ग्रामीण कार्यकर्ता व जन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शरीक हुए, लेकिन डा० साधो बैठक में भाग लेने के बजाय एक रोज पहले भोपाल पलायन कर गयीं। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि सुभाष यादव खरगौन जिला कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक में पिता-पुत्री के खिलाफ असंतोष फूट पड़ा और उनके कारनामों के कारण म०प्र० सेवा दल के संयुक्त सचिव दुबे समेत अनेक लोगों ने उन्हें जी भर कर कोसा। इस पर सांसद यादव को यह आश्वासन कार्यकर्ताओं को देना पड़ा कि वह उनकी भावनाओं से उच्च नेताओं को अवगत करा देंगे।

उपेक्षा : विधानसभा की महेश्वर सीट पर १९५२ से साधो परिवार का वर्चस्व है, किंतु इस परिवार ने हरिजनों के प्रति प्रायः उपेक्षा ही बरती है। सीताराम राजनीति में ज्यों-ज्यों रमे अपने गुरु और गांधीवादी नेता जुड़ावचंद जैन की सीखों को त्यों-त्यों भूलते गये। उन पर हरिजन छात्रावास की जमीन हड़पने का भी आरोप है। उन्होंने छात्रावास की भूमि-खसरा क्र० ३४१, रकबा ६.४१ एकड़, लगान ९ रुपए ५६ पैसे और खसरा क्र० ३६५, रकबा ३.०९ एकड़, लगान १६ रुपए ४५ पैसे—पहले स्वयं और फिर अपनी पत्नी श्रीमती देवकी बाई (पत्नी सीताराम हरिजन) के नाम पर नामांतरित करायी। यह कार्य उन्होंने म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा-१९० के तहत तत्कालीन नायब तहसीलदार धुले से तब कराया था, जब वह संसदीय सचिव थे। साधो परिवार के सभी सदस्य हालांकि अब भोपाल में रहते हैं, किंतु महेश्वर में छात्रावास कीं जमीन पर आज भी साधो परिवार का कब्जा है और उसका एक हिस्सा किराये पर दे दिया गया है। बताते हैं कि इस भवन में छात्रावास कुछ ही दिन रहा और हरिजन नेता होने के नाते अधीक्षक बनाये गये सीताराम साधो ने जमीन और इमारत पर काबिज होने की नीयत से छात्रावास से हरिजन छात्रों को एक-एक कर बेदखल कर अन्यत्र भेज दिया। शासन ने साधो की संस्था हरिजन मंडल को गांधी शिक्षण कला मंदिर व हरिजन छात्रावास के लिए १९५२ से १९५६ के मध्य २१,३०० रुपए का अनुदान दिया था और स्कूल एवं होस्टल के नाम पर चंदा भी वसूला गया, जिसके हिसाब-किताब का आज तक अता-पता नहीं है।

साधो परिवार के कारनामों की कथा यहीं खतम नहीं होती। भीला (पिता धन्ना मिस्त्री, निवासी कवड़िया) ने मंडलेश्वर के थानेदार को अर्जी देकर कहा है कि सीताराम साधो से उसे जान का खतरा है और उन्होंने उसके पीछे इस प्रयोजन से दो लोगों को लगा रखा है। इस अर्जी की प्रतियां भीला ने राजीव गांधी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और सुभाष यादव को भेजकर प्राण-रक्षा करने की याचना की है।

छाया: आर०सी० साहू

—सुधीर सक्सेना

विधायक बनाम पुलिस अधीक्षक

क्या प्रभुनाथ सिंह आतंककारी हैं?

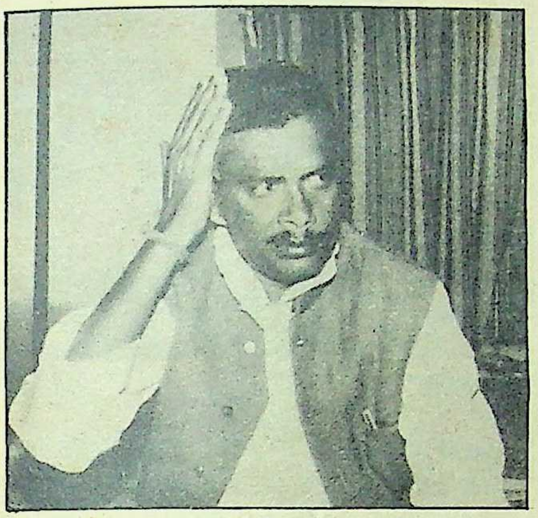

तनाव का कारण क्या है? : प्रभुनाथ सिंह

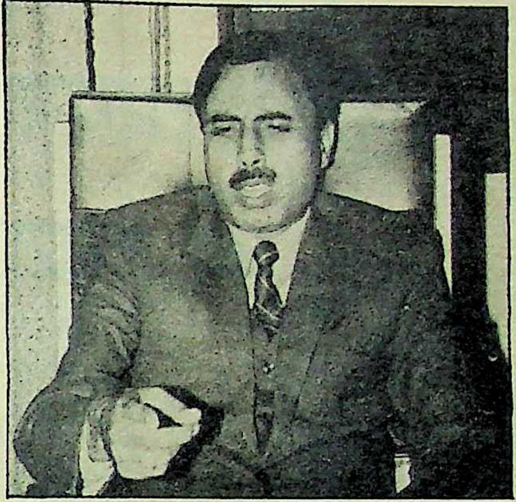

विधायक से जान को खतरा : पुलिस अधीक्षक खन्ना

ऐसा बिहार में ही संभव है कि कोई पुलिस अधीक्षक सरकार से इस बात की गुहार करता हो कि एक विधायक से उसकी जान को खतरा है। सारण के पुलिस अधीक्षक जे०के० खन्ना ने सारण जिले के ही मसरख क्षेत्र से निर्दलीय विधायक प्रभुनाथ सिंह पर यही आरोप लगाया है। नतीजतन, विधायक सिंह और पुलिस अधीक्षक खन्ना के बीच बात कुछ इस कदर ठन गयी है कि जहां एक तरफ प्रभुनाथ सिंह के समर्थन में लगभग पचास विधायक जे०के० खन्ना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वहीं सात विधायकों ने खन्ना की तरफदारी में सरकार से मांग की है कि खन्ना को परेशान न किया जाये, क्योंकि वह एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं।

खन्ना पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विधायक प्रभुनाथ सिंह ने जब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को विस्तृत विवरण दिया, तो विशेषाधिकार समिति ने पुलिस अधीक्षक खन्ना को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। खन्ना शायद इसी मौके की ताक में थे। लिहाजा, विधानसभा के उपसचिव महेश्वर प्रसाद के नाम प्रेषित अपने बीस पेजी स्पष्टीकरण में खन्ना ने विधायक प्रभुनाथ सिंह को आड़े हाथों लिया और प्रभुनाथ पर कई संगीन आरोप लगाये। अपने स्पष्टीकरण में खन्ना ने लिखा, "श्री प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध यदाकदा कोई-न-कोई आवेदन प्राप्त होता रहा है। इनके आतंक के संबंध में एक हवाला देना चाहूंगा जो मसरख के भूतपूर्व इंका विधायक डा० हरेन्द्र किशोर सिंह ने दिनांक १७ अगस्त, १९८७ को मेरे पास भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता श्री रामदेव सिंह, तत्कालीन विधायक (मसरख) की हत्या का मामला छपरा न्यायालय में चल रहा है जिसकी अगली तारीख १९ अगस्त, १९८७ थी। इस कांड में प्रभुनाथ सिंह विधायक अभियुक्त हैं। डा० हरेन्द्र किशोर सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि वह न्यायालय में अगली तारीख को पूरे दलबल के साथ हथियारों से लैस होकर कोई अप्रिय घटना करा सकते हैं।

"अब मैं श्री प्रभुनाथ सिंह से पूर्व अपराध इतिहास की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कार्यालय की संचिका देखने से पता चलता है कि श्री सिंह हत्या, चोरी, दंगा एवं अन्य प्रकार के कांडों में संलग्न रहे हैं, जिनका पूरा विवरण नीचे दिया जा रहा है। इनमें से अधिकतर कांडों में उनके भाई दीनानाथ सिंह भी उनके साथ शामिल रहे हैं :—

१-मसरख थाना, कांड संख्या—४, दिनांक १६-८-७६ धारा ३७९ भा०द०वि०, चोरी कांड। इस कांड में माननीय विधायक एवं अन्य दो पर आरोप पत्र दाखिल किया गया।

२-मसरख थाना, कांड संख्या—१, आवश्यक १५-११-८०, धारा ३७९/३४ भा०द०वि०, चोरी कांड। इस कांड में विधायक और उनके भाई दीनानाथ सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

३-मसरख थाना कांड संख्या—१, आवश्यक वस्तु अधिनियम कालाबाजारी का कांड। इस कांड में विधायक और उनके भाई दीनानाथ सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

४-मसरख थाना, कांड संख्या—१६, दिनांक ३०-१०-८०, धारा ३०७/३२६/३०२ भा०द०वि० एवं २७ आर्म्स एक्ट, हत्याकांड। इस कांड में विधायक और उनके भाई के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

५-सिवान रेल थाना कांड, संख्या—२ (१) ८१, धारा ३०७/३२६ भा०द०वि० एवं २७ आर्म्स एक्ट, मारपीट एवं गोली कांड। इस कांड में भी विधायक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल।

६-मसरख थाना, कांड संख्या—१६/८२, दिनांक १९-१-८२ धारा १४३/३४१/३४२/३२३ भा०द०वि०, मारपीट का कांड। यह कांड रेलवे पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस कांड में धारा ३२३ भा०द०वि० के अन्तर्गत विधायक और उनके भाई दीनानाथ सिंह के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन (असंज्ञेय) दाखिल किया गया।

७-मसरख थाना, कांड संख्या—१२८/८३ दिनांक २०-७-८२, धारा ४२०/२२५/३४ भा०द०वि०, ठगी कांड। इस कांड में विधायक एवं दो अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

८-मसरख थाना, कांड संख्या—१४८/८४ दिनांक १९-१०-८४, धारा १४३/१४४ भा०द०वि० एवं २७ आर्म्स एक्ट, दंगा एवं गोली कांड। इस कांड में विधायक के अतिरिक्त उनके भाई एवं छह अन्य लोगों का भी नाम आया है। कांड की खोजबीन जारी है।

९-मसरख थाना, कांड संख्या—३१/८५ दिनांक २-३-८५ धारा ३०७/३४, भा०द०वि० एवं ३/४ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। हत्या का प्रयास किये जाने का कांड।

१०-छपरा नगर थाना, कांड संख्या—१७५/८५ दिनांक १८-७-८५, धारा १८६/३५३/४४८/५०४/५०६, भा०द०वि०। इस कांड में प्रभुनाथ सिंह एवं अन्य छह-सात अज्ञात व्यक्ति प्राथमिकी अभियुक्त हैं। इस कांड में जांच के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन धारा ५०४/५०६ भा०द०वि० के अंतर्गत (असंज्ञेय) प्रतिवेदन दाखिल किया गया।

अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त मामलों का ब्यौरा देते हुए पुलिस अधीक्षक खन्ना ने लिखा है कि जून, १९८७ से इस जिले में मेरे योगदान के पश्चात प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध एक भी कांड दर्ज नहीं किया गया है। यदि मुझे उनसे व्यक्तिगत रंजिश होती, तो मैं उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करता।

पुलिस अधीक्षक खन्ना द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रसंग में विधायक प्रभुनाथ सिंह कहते हैं कि ऐसा पुलिस अधीक्षक जिसे एक विधायक से जान का खतरा महसूस हो, वह जिले की रक्षा किस कूवत पर कर सकता है। प्रभुनाथ कहते हैं कि खन्ना का जिस समय सारण के लिए स्थानांतरण हुआ था उसी समय मैंने विधानसभा में उनका विरोध किया था। मैंने खन्ना के बारे में सदन में कहा था कि यह वही अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी तस्करी में एक बार पकड़ी गयी थी। मैं इनके कारनामों से पूर्व से वाकिफ था, इसलिए शुरू में ही मैंने जिले में इनके आगमन का विरोध किया था। खन्ना तभी से मुझसे खार खाये बैठे हैं। भूमि विकास बैंक के चुनाव के दौरान भी इन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को परेशान करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। १३ अक्तूबर, १९८७ को खन्ना ने मुझे मसरख के गेस्ट हाउस में बुलवाया। वहां मुझे चेतावनी दी कि मैं उनकी आलोचना न करूं। नतीजतन, खन्ना द्वारा दुर्व्यवहार के इस मामले के संबंध में मैंने विधानसभा

की विशेषाधिकार समिति को लिखा। अगर मुख्यमंत्री ने खन्ना का तत्काल तबादला नहीं किया तो पूरे सारण जिले में जनांदोलन को कोई रोक नहीं सकेगा।''

आखिर विधायक प्रभुनाथ व पुलिस अधीक्षक खन्ना के बीच तनाव का कारण क्या है? इसका खुलासा स्थानीय लोग करते हैं। दरअसल, यह सारण जिले के यादव बनाम राजपूत झगड़े का नतीजा है। दुबे सरकार में काबीना मंत्री राम जयपाल सिंह यादव ने खन्ना का पदस्थापन सारण में करवाया। राम जयपाल यों अपने गृह जिले के बजाय बख्तियारपुर से विधायक हैं, लेकिन अपने गृह जिले की राजनीति में उनकी दिलचस्पी रहती है। सारण जिले की राजनीति में यादवों और राजपूतों की हरदम से ठनी रही है। सारण जिले के दस विधानसभाई क्षेत्र में छह स्थान पर यादव विधायक, दो पर राजपूत, एक पर हरिजन और एक क्षेत्र से भूमिहार विधायक है। निर्दलीय विधायक प्रभुनाथ सिंह यादवों के मुखर विरोधी हैं। यों मसरख के पूर्व कांग्रेसी विधायक डा० हरेन्द्र किशोर सिंह से भी प्रभुनाथ की तनातनी है, क्योंकि एक तो हरेन्द्र के पिता और मसरख के पूर्व विधायक रामदेव सिंह की हत्या से संबंधित मुकदमे में विधायक प्रभुनाथ सिंह का भी नाम है और दूसरे चुनाव में हरेन्द्र प्रभुनाथ से हार चुके हैं।

पिछले दिनों भूमि विकास बैंक के चुनाव में फिर प्रभुनाथ का हरेन्द्र किशोर से सामना हुआ। क्षैत्रीय इंका सांसद कृष्ण प्रताप सिंह हरेन्द्र की मदद में थे। इस चुनाव में प्रभुनाथ ने हरेन्द्र को मात दी। चुनाव में शक्ति प्रदर्शन जम कर हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्रभुनाथ सिंह का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक खन्ना ने उनके विरोधियों को कुछ नहीं किया और सिर्फ उनके समर्थकों को ही परेशान किया। प्रभुनाथ को इस बात की भी नाराजगी हुई कि मसरख के अफसर इंचार्ज रामनरेश सिंह, जो उनके प्रति सद्भाव रखते थे, का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक खन्ना ने कर दिया। खन्ना द्वारा दिये गये कांडों के विवरण पर प्रभुनाथ कहते हैं कि पूर्वाग्रह के शिकार खन्ना ने उन मामलों का भी जिक्र किया है ज़ो कब के खतम हो चुके हैं।

बहरहाल, खन्ना और प्रभुनाथ का झगड़ा रोज तूल पकड़ता जा रहा है। यों प्रभुनाथ पचासेक विधायकों से यह मांग करवा रहे हैं कि खन्ना को सारण जिले से हटा दिया जाये, पर खन्ना के स्थानांतरण के आसार कम ही हैं, क्योंकि सांसद कृष्ण प्रताप सिंह इन दिनों दुबे के प्रिय सिपहसालार हैं। प्रभुनाथ, कृष्ण प्रताप की आंखों की किरकिरी हैं, इसलिए प्रभुनाथ खन्ना हटाओ मुहिम में शायद ही कारगर हो पायें। दूसरे, कबीना मंत्री राम जयपाल सिंह यादव का भी अनुग्रह खन्ना को प्राप्त है। इसलिए देखना है कि आखिरकार जीत किसकी होती है?

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

कुएं के लिए पूर्व विधायक की हत्या

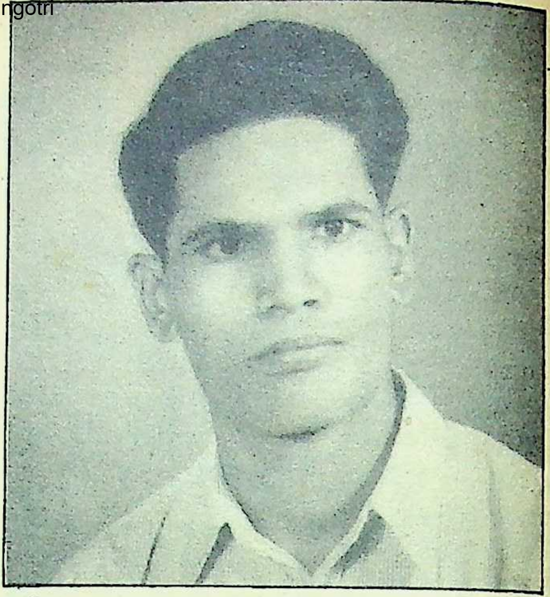

खुदिया पाहन

महज एक कुएं की मिल्कीयत के सवाल पर खूंटी के पूर्व भाजपा विधायक खुदिया पाहन जान से हाथ धो बैठे। रांची से तकरीबन ४२ किलोमीटर पूरब में स्थित महली गांव में ३ दिसंबर की रात विगत एक साल से चले आ रहे कुएं के मामूली विवाद में सिर्फ खुदिया पाहन ही नहीं उनकी पत्नी रूपचांद और दो पुत्र २२ वर्षीय जयंत पाहन और १२ वर्षीय कुंजल पाहन भी मौत के घाट उतार दिये गये।

घटना: घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह खुदिया पाहन के ७३ वर्षीय पिता सोमा पाहन ने 'माया' को बताया कि ३ दिसंबर की रात आठ बजे तलवार, टांगी, फरसा आदि घातक हथियारों से लैस व्यक्तियों का एक जत्था अचानक दालान से होते हुए उनके घर में घुसा और खाना खाकर आराम कर रहे खुदिया पाहन पर एकबारगी टूट पड़ा। उस वक्त खाना खा रहे उनके दो बेटे जयंत सिंह पाहन एवं कुंजल सिंह पाहन, जब अपने पिता को बचाने के लिए बढ़े, तो हत्यारों नें उन दोनों को भी वहीं ढेर कर दिया। शोर-शराबा सुनकर रसोई घर से खुदिया पाहन की पत्नी रूपचांद जैसे ही बाहर निकली कि हमलावरों ने उन्हें भी जमीन पर पटक कर गला रेत डाला। सोमा पाहन कहते हैं कि जब मैंने इसका विरोध किया, तो मुझे भी बुरी तरह से पीटा गया। जाते-जाते हत्यारों ने कहा—बूढ़े, तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जब तक जियो तब तक याद रखो कि हमारी खिलाफत का परिणाम क्या होता है।''

आखिर खुदिया की हत्या क्यों हुई और हत्यारे कौन थे? इसे जानने के लिए एक साल पीछे लौटना पड़ेगा। दरअसल, खुदिया पाहन के दालान के निकट बने कुएं के स्वामित्व व उसके पानी के उपयोग के सवाल को लेकर पिछले एक साल से विवाद चल रहा था। इस कुएं का निर्माण खुदिया पाहन ने स्वयं अपने विधायक काल के दौरान करवाया था। शुरू-शुरू में सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन बाद में खुदिया पाहन ने इस सार्वजनिक कुएं के पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी शुरू की। उनके भतीजे भी कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे। नतीजतन, खुदिया के भतीजों ने गांव में कुछ लोगों को लेकर अपने चाचा का विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि कुआं सार्वजनिक है, लिहाजा इसके पानी का इस्तेमाल गांव का हर आदमी करेगा। इस झगड़े का अंत परिवार समेत खुदिया की हत्या से हुआ।

पुलिस ने मृत विधायक व घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह खुदिया पाहन के पिता सोमा पाहन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी के अनुसार खुदिया के चाचा नीलांबर पाहन, खुदिया के चार चचेरे भाई पटिवाल पाहन, प्रकाश पाहन सुभाष पाहन एवं अमर सिंह के अतिरिक्त गांव के ही दो नौजवान दलु मुण्डा और अनिल महतो हत्याकांड में शरीक थे।

मृत विधायक खुदिया पाहन के एक पुत्र कुंवर सिंह पाहन जो घटना के वक्त गांव में नहीं थे का कहना है कि उनके परिवार को खतम करने की योजना काफी पहले से बन रही थी।

पूर्व विधायक के परिवार में अब बूढ़े पिता के अलावा तीन सदस्य बचे हैं। बचे हुए इन सदस्यों में एक पुत्र मंगल सिंह पाहन एवं एक पुत्री रुकमणी है। रांची के वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक आर०ई०वी० कुजुर से भेंट की, तो उन्होंने कहा कि खुदिया पाहन के परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है और हत्यारों को पकड़ने की भरपूर क़ोशिश की जा रही है।

भाजपा के पूर्व विधायक ननी गोपाल मित्रा ने मांग की कि खुदिया पाहन के हत्यारों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाये। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विश्व हिंदू परिषद के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं की हत्या इसी तरह की जा रही है। महली में पुलिस-गश्त जारी है, लेकिन खुदिया के पिता आश्वस्त नहीं हैं। वह कहते हैं, ''हत्यारे कभी भी मेरी जान ले सकते हैं।''

—प्रकाश चन्द्र

दुबे के हजार दिन

हिंदीभाषी प्रांतों में बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व में हजार दिन पूरे होने की खुशी में एक ओर उनकी लाबी के लोग जश्न मना रहे थे और दूसरी ओर उनके विरोधियों में उनके तख्ता पलटने की साजिश चल रही थी। दुबे को उखाड़ने में कौन लोग लगे हैं और उनके दांवों को दुबे और उनकी लाबी कैसे काट रही है?

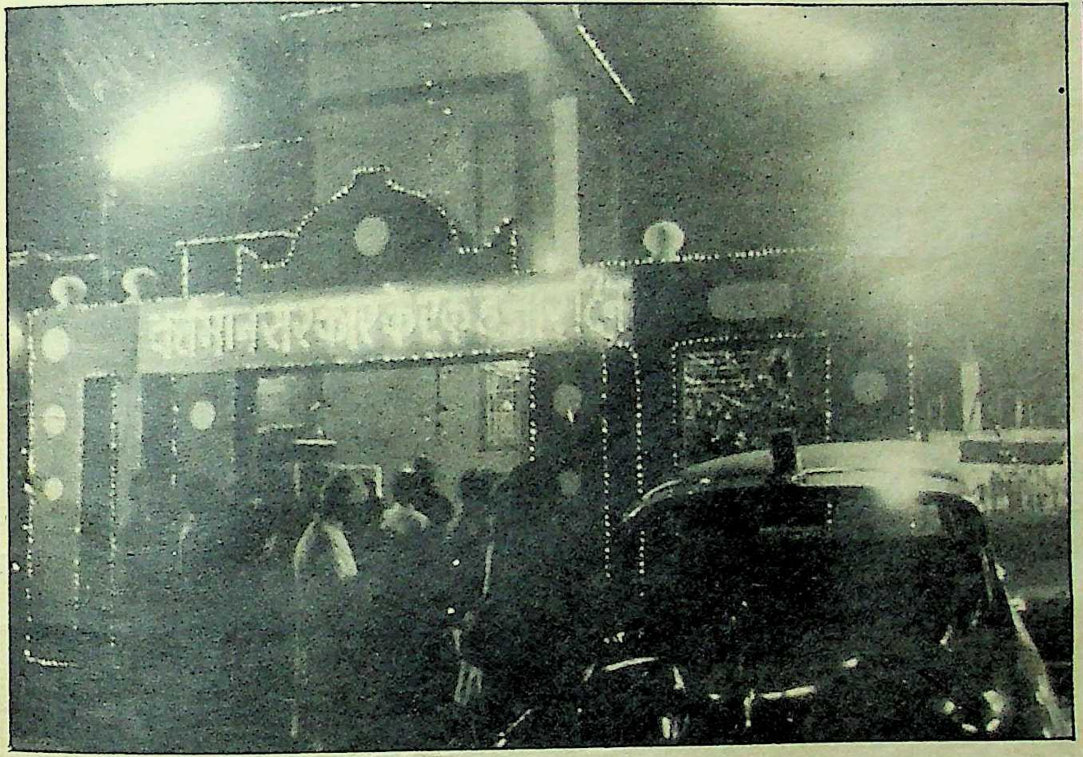

स्याह शासन को चमकाने की कोशिश

हजार दिन तो पूरे हो ही गये : बिंदेश्वरी दुबे

हजार दिन दुबे के, तो एक दिन हमारा भी— यह टिप्पणी बिन्देश्वरी दुबे से सख्त नाराज इंका के एक हरिजन सांसद की है। सात दिसंबर को मुख्यमंत्री दुबे की सरकार के एक हजार दिन पूरे हो रहे थे, लेकिन अपनी हुकूमत के ९९७वें दिन दुबे दिल्ली में अचानक अपनी लड़खड़ायी लाबी को दुरुस्त करने में बेहाल थे। १२ मार्च, १९८५ को जब दुबे बिहार के सिंहासन पर काबिज हुए थे, उसके बाद से यह पहला मौका था कि बिहार के अधिकांश इंका सांसदों ने एकबारगी गुस्से में दुबे के विरुद्ध हल्ला बोल दिया। भूचाल अगर पटना से उपजा हो, तो मिनटों में उसे कैसे दबाया जाता है, इस गुर को दुबे कई बार सफलतापूर्वक आजमा चुके हैं। पर दिल्ली से उठा बवंडर काफी जटिल होता है। अगर खुद इंका के 'परमपिता' के इशारे पर कुछ हो रहा हो, तो उसे रोकना भी धृष्टता ही समझी जाती है। दुबे सचमुच विचलित थे कि हजार दिन लगने में बस दस-ग्यारह दिन शेष हैं और यह तूफान!

२५ नवंबर को बिहार के तकरीबन तीस सांसदों ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का एक मात्र विषय था—'बिन्देश्वरी दुबे'। अधिकांश सांसद बिलकुल सुलग रहे थे। यों उन सांसदों की नाराजगी का भीतरी सबब अलग-अलग था, लेकिन घोषित रूप से दुबे की भर्त्सना के लिए बैठक में दो-तीन मुद्दे उठाये गये कि बिहार का मौजूदा नेतृत्व प्रदेश के विकास में बिलकुल नकारा साबित हुआ है। बाढ़-सूखे के बाद राहत कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सुस्ती बरती गयी और ढीले प्रशासन के कारण भ्रष्टाचार का वातावरण पूरे प्रदेश में कायम है। सांसदों का आक्रोश इस पर भी था कि मुख्यमंत्री ने कभी उन लोगों को भरोसे में नहीं लिया और जब कभी अपने चुनाव क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से मौखिक या पत्र द्वारा लोगों ने अनुरोध किया, तो कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सांसद बैठक में आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री को बिहार की बदइंतजामी से अवगत कराया जाये और नेतृत्व-परिवर्तन की मांग की जाये। बैठक में गठित पांच सांसदों की समिति (जिसमें तारिक अनवर, किंग महेन्द्र, डा० मनोज पाण्डेय, सरफराज अहमद और रामस्वरूप राम थे) को जिम्मेदारी सौंपी गयी कि प्रधानमंत्री को बिहारी सांस्दों के दुख का ब्यौरा दें। बैठक की रात ही जब मुख्यमंत्री समर्थक एक सांसद ने दूरभाष पर मुख्यमंत्री निवास को सूचना दी, तो अगली सुबह तक पटना के ठंडाये हुए राजनीतिक अलाव में गरमाहट आ गयी। वैसे पिछले दो-ढाई महीनों से बिहार की राजनीति एकदम शांत थी। बागी नेता डा० जगन्नाथ मिश्र के तेवर भी भोथरे हो रहे थे। पर सांसदों के इंकलाब ने अनायास बिहार-राजनीति को गहरी नींद से जगा दिया। बिहार सरकार वैसे पटना में थी, लेकिन सारी शक्ति दिल्ली में जुटी थी। सबसे पहले कोशिश यह की गयी कि पांच सदस्यीय समिति के सदस्यों से बैठक की बात का खंडन करा दिया जाये, पर वैसा संभव नहीं हो सका। इस समिति के सदस्य सेवादल के अध्यक्ष तारिक अनवर का संवाद सीधे आलाकमान से है। दूसरे गिरीडीह के सांसद सरफराज अहमद तारिक के पुराने शिष्य हैं। गया से हरिजन सांसद रामस्वरूप राम सीताराम केसरी के 'माउथ-पीस' कहे जाते हैं और किंग महेन्द्र सीधे

माखनलाल फोतेदार के दरबारी माने जाते हैं। जाहिर था कि तारिक, केसरी और दिल्ली दरबार की निकटस्थ ताकतवर लाबी दुबे के तख्ता पलट में जुटी थी।

भोज की राजनीति: दुबे इस विद्रोह को सफायी से कैसे खारिज करें, इस समीकरण पर दुबे के दरबारी माथापच्ची कर रहे थे। आखिरकार तय यही हुआ कि दुबे खुद दिल्ली जायें और सांसदों को मनायें। सचमुच इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। ३ दिसंबर को बिहार सरकार के विमान से दुबे दिल्ली के लिए उड़ गये। खिसियाये सांसदों से कैसे मिला जाये, इसकी एक रोचक युक्ति प्रदेश इंका अध्यक्ष डुमर लाल बैठा ने जब दुबे को बतायी, तो दुबे गद्गद हो गये। वाकई बैठा भी कभी-कभी दूरदर्शिता की झलक दिखा देते हैं। आज से तीन-चार माह पूर्व बैठा को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी। लिहाजा, बैठा ने ऐन ३ दिसंबर को जिस दिन दुबे दिल्ली पहुंचे, अपने फिरोजशाह मार्ग स्थित निवास पर 'पुत्र जन्मोत्सव' का आयोजन किया। तमाम सांसद निमंत्रित किये गये। साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू, वेस्टर्न कोर्ट, अकबर रोड, राजेन्द्र प्रसाद रोड आदि तमाम इलाकों में स्थित बिहारी सांसदों के निवास के दूरभाष हलचल में आ गये। सभी सांसद वाकिफ थे कि भोज का उद्देश्य क्या है? फिर भी, मुख्यमंत्री की 'तबीयत' भांपने का कौतूहल कोई नहीं पचा पा रहा था। लिहाजा, बैठा के आयोजन में अधिकांश सांसद आये। पर आयोजन की समाप्ति के बावजूद सांसदों के नासूर ज्यों-के-त्यों रहे। दिल्ली में दुबे की लाबी वाले सांसद कृष्ण प्रताप सिंह, 'कोआपरेटिव किंग' तपेश्वर सिंह सहित कुछ चुनिंदा सांसद अगले दिन के 'शो' को कारगर करने में जुटे थे। फिर तय यह हुआ कि सांसदों से सीधे बातचीत करने के लिए एक भोज और किया जाये। केंद्रीय राज्यमंत्री रामानंद यादव के मत्थे भोज की जिम्मेदारी डाली गयी। ४ दिसंबर की शाम रामानंद के राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित

ज्योतिषियों की नजर में दुबे-राज

कमलाकांत झा

पं० गणेश कांत

श्रीमती मंजु मधुकर

कहते हैं कि राजा के भाग्य से ही राज्य की तकदीर जुड़ी होती है। राजा की ग्रहदशा दुरुस्त हो, तो प्रजा भी सुख से जीती है और अगर ग्रह-नक्षत्रों की भृकुटि राजा पर टेढ़ी हो, तो प्रजा की स्थिति दयनीय होती है। मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे की सरकार जबकि हजार दिन पार करके १९८८ में दाखिल हो चुकी है, ऐसे में बिहार का भाग्य कैसा रहेगा? स्वयं मुख्यमंत्री दुबे की स्थिति कैसी रहेगी और दुबे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ग्रह-नक्षत्र कैसे रहेंगे? इन तमाम सवालों का खुलासा बिहार के प्रमुख ज्योतिषियों ने 'माया' के लिए किया है।

बिहार सरकार के राज्य ज्योतिषी पंडित चक्रधर झा शास्त्री की गणना के अनुसार वर्ष १९८८ में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति काफी गंभीर रहेगी। बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल पर शनि की कुदृष्टि है। बिहार, क्योंकि नाम से वृष राशि में पड़ता है और वृष राशि पर शनि की अढ़ैया का प्रकोप है, इसलिए प्रदेश की सामान्य स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे भी, क्योंकि प्रचलित नाम से वृष राशि के हैं, इसलिए शनि की अढ़ैया का कुप्रभाव उन पर भी पड़ सकता है। पर चूंकि मुख्यमंत्री दुबे का भाग्येश शनि और कर्मेश भी शनि है, इसलिए यह उनको कुछ राहत दे सकता है। प्रदेश में इस वर्ष अपराधों में और अधिक वृद्धि होगी। हां, कृषि और व्यापार के लिए यह वर्ष आशाजनक रहेगा।

मुख्यमंत्री दुबे के प्रबल राजनीतिक विरोधी डा० जगन्नाथ मिश्र के वर्ष १९८८ में भविष्य की गणना करते हुए सरकारी ज्योतिषी चक्रधर झा कहते हैं कि डा० मिश्र के लिए यह वर्ष उत्तम साबित होगा। कांग्रेस के पूर्व महासचिव भागवत झा आजाद की स्थिति भी इस वर्ष और सुदृढ़ होगी। बिहार मंत्रिमंडल में वर्ष १९८७ में सर्वाधिक विवादास्पद मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह के लिए १९८८ भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि रामाश्रय शनि की साढ़ेसाती के प्रकोप से अब मुक्त हो चुके हैं। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर के लिए यह वर्ष उथल-पुथल का रहेगा।

सत्ता-परिवर्तन की सम्भावना: पटना की एकमात्र महिला ज्योतिषी श्रीमती मंजु मधुकर की गणना के मुताबिक १९८८ बिहार के सामान्य जन के लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा। जनता की समस्या सुलझने के बजाय बढ़ेगी ही। १९८८ के वर्ष लग्न में शनि और मंगल एक साथ दशम स्थान में हैं और उनकी दृष्टि चूंकि चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जनजीवन कष्टमय रहेगा। उत्तर-पश्चिम दिशा में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका है। साथ ही फरवरी-मार्च के बीच प्रदेश में कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बिहार की कुंडली में इस वर्ष स्थान पर शनि और मंगल आ रहा है। इसलिए यह कष्ट और अमंगल का सूचक है। प्रदेश में मई-जून के आसपास सत्ता-परिवर्तन हो सकता है। कृषि और व्यापार की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

ज्योतिषाचार्य पंडित कमलाकांत झा के अनुसार, १९८८ में बिहार के लिए गुरु एवं शनि प्रतिकूल हैं, इसलिए यह वर्ष सुंदर संभावनाओं का नहीं कहा जा सकता। बाढ़ व सूखे का फिर प्रकोप हो सकता है। अपराध में वृद्धि की पूरी संभावना। मुख्यमंत्री दुबे केंद्र में आ सकते हैं। डा० जगन्नाथ मिश्र के लिए यह वर्ष प्रभाव में वृद्धि लायेगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा शाही के लिए राजनीतिक उत्कर्ष का वर्ष है। बिहार सरकार में काबीना मंत्री रामाश्रय सिंह के लिए उत्तम वर्ष।

ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश कांत की गणना का फलाफल है कि १९८८ बिहार के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि इसका वर्ष-प्रवेश त्रयोदशी शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र शुभयोग ववकरण से आरंभ होने जा रहा है। प्रांत ? किसी बड़े राजनेता से वंचित हो सकता है। मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे के लिए यह वर्ष राजभंजक योग से युक्त है। डा० जगन्नाथ मिश्र के लिए १९८८ के १५ मार्च से बाद का समय अकस्मात प्रतिष्ठा व पदप्राप्ति का योग लायेगा। शनि की अढ़ैया के समाप्त होने से रामाश्रय प्रसाद सिंह की राजनीतिक स्थिति में सुधार आयेगा।

—विकास कुमार झा

सहकारी किंग तपेश्वर सिंह (बायें), दुबे (बीच में), राधानंदन झा (दायें)

निवास पर भोज का जबर्दस्त सरंजाम था, पर सांसदों की मौजूदगी अपेक्षा से कम थी। कृष्ण प्रताप और तपेश्वर सिंह के अतिरिक्त ललितेश्वर प्रसाद शाही, सुमति उरांव, महेन्द्र मोहन मिश्र, तिलकधारी सिंह, दामोदर पाण्डेय और रामश्रेष्ठ खिरहर आदि हाजिर थे। तारिक-केसरी खेमे के क्षुब्ध सांसदों ने इस भोज का 'बायकाट' किया। डुमरलाल बैठा के यहां आयोजित भोज को भी जब दुबे समर्थकों ने अपने पक्ष में यह प्रचारित किया कि वहां मौजूद तमाम सांसदों ने दुबे के प्रति आस्था व्यक्त की, तो प्रतिक्रियास्वरूप ६ दिसंबर को सांसद रामस्वरूप राम इस प्रचार का ही खंडन करने पटना आ गये और ७ दिसंबर को बाकायदा बयान देकर इस बात का खंडन किया कि बैठा के घर आयोजित भोज राजनीतिक नहीं 'पारिवारिक' था। वहां कांग्रेस के अलावा दूसरे दल के सांसद भी जुटे थे, इसलिए उस उपस्थिति को अपनी राजनीति के लिए प्रचारित करना अनुचित है। रामस्वरूप राम ने इतना स्वीकार किया कि केंद्रीय राज्यमंत्री रामानंद यादव के घर का भोज दुबे के समर्थन में हुआ था, पर उसमें दर्जन से अधिक सांसद नहीं थे।

ऐसी नाराजगी क्यों? : आखिर सांसदों ने अचानक यह बवाल क्यों किया और इसके सूत्रधारों की नीयत क्या है? इस सवाल का जवाब राजनीतिक खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल, 'सहकारी नरेश' तपेश्वर सिंह उन्हीं के गुट के कृष्ण प्रताप सिंह आदि की लाबी को दुबे द्वारा ज्यादा अहमियत दिये जाने से अधिकांश सांसद क्षुब्ध थे। इस क्षोभ का ही इस्तेमाल केसरी-तारिक व अन्य दुबे विरोधियों ने किया। तारिक अनवर के कुछ शिष्यों को बिहार के निगमों में जगह देने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया था। पर तारिक के उत्साही सेवकों को दिखाया गया सपना दुबे ने पूरा नहीं किया। जहानाबाद के अपने समर्थक विधायकों की उपेक्षा से किंग महेन्द्र भी नाराज चल रहे हैं। केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णा शाही तो मुख्यमंत्री की मुखर आलोचक हैं। फिर दिल्ली में मौजूद बुजुर्ग सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह हों, भागवत झा आजाद हों, प्रभावती गुप्ता हों या फिर बलिराम भगत, सब-के-सब दुबे से क्षुब्ध रहते ही हैं और जब दुबे के खिलाफ पलीता लगाने की तैयारी होती है, तो परोक्ष रूप से ही सही ऐसे दिग्गजों का सहयोग मिल ही जाता है। एक क्षुब्ध सांसद कहते हैं कि दुबेजी में एक बहुत बड़ी कलात्मकता है कि वह अरसे तक किसी को बहलाये रख सकते हैं। सीतामढ़ी के सांसद रामश्रेष्ठ खिरहर विगत एक साल से मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। कई बार उन्हें आश्वासन मिला कि किसी निगम आदि का अध्यक्ष पद उन्हें दे दिया जायेगा, पर खिरहर की मुराद अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर भी वह पूरे धैर्य से मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित हैं। पटना के सांसद डा० सी०पी० ठाकुर देखते हैं कि उनकी बिरादरी के जितने घाघ राजनेता हैं, वे उन्हें हरगिज फलने-फूलने नहीं देंगे। लिहाजा, 'मुख्यमंत्री एक तेरा सहारा' जैसा मामला उनका भी है। दामोदर पाण्डेय और तिलकधारी सिंह दुबेजी के पुराने भक्त रहे हैं। ललितेश्वर प्रसाद शाही की भी राजनीति जर्जर है। इसलिए 'बाबा नाम केवलम' के सिवा उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली-अभियान में दुबेजी तीन दिन तक दिल्ली को छानते रहे। इस यात्रा में प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। ६ दिसंबर को यानी एक हजार दिन पूरे होने के बस एक दिन पहले दुबेजी पटना आये। पर पटना में हजार दिन की तैयारी में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। 'बिहार नागरिक परिषद' के उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभाध्यक्ष राधानंदन झा ने दुबे सरकार के 'बर्थ डे' का अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था। राधानंदन की मस्केबाजी से दुबे के अन्य दरबारी खिन्न रहते हैं। हजारवें दिन पर राधानंदन ने भाषण में कामना की —"दुबेजी, हजार दिन ही क्यों, अपनी अंतिम सांस तक बिहार के मुख्यमंत्री रहें।" दुबे के कुछ दरबारी झुंझलाकर कहते भी हैं—"पता नहीं 'बाबा' को इस आदमी से क्यों लगाव है?" पर दुबे के एक खासुलखास कहते हैं कि राधानंदन के बारे में बाबा कहते हैं, "विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका यह आदमी मेरे लिए क्लर्क की तरह काम

पुत्र जन्मोत्सव के बहाने दुबे का समर्थन : डुमरलाल बैठा

दुबे के विरुद्ध मुहिम : तारिक अनवर

१ जनवरी तक प्रकाश्य

मनोरमा

जनवरी प्रथम पक्ष १९८८

व्यंजन विशेषांक

चटपट-झटपट बननेवाली व्यंजन विधियां

विशेष रचनाएं

- झटपट बनें जैम, चटनी और अचार
- एक व्यंजन : संपूर्ण भोजन
- व्यंजन मुगलाई दस्तरख्वान से
- घणों चोखो खाणो मारवाड़ रो
- सूप और शोरबे : नयी पेशकश, नये स्वाद
- दावती खाना 'दावत' का
- पिट्जा : नये ढंग, नये स्वाद
- पुडिंग व मीठे व्यंजन
- विदेशी व्यंजन : शाकाहारी व मांसाहारी
- बर्थ-डे केक
- नयी उमर की नयी पसंद

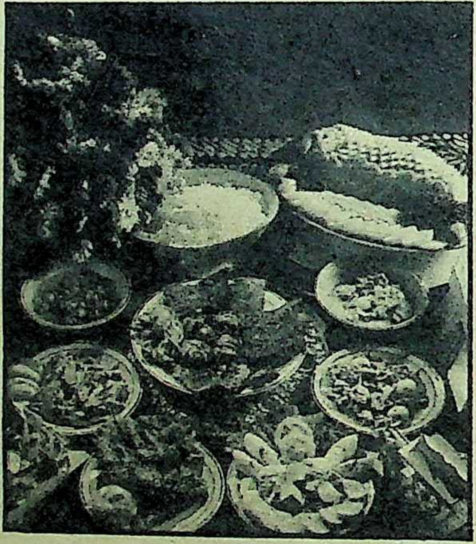

आवरण कथा :

क्या आधुनिक महिलाओं के लिए रसोई एक कैद है ?

क्या पढ़ी-लिखी रसोई के काम में लगी महिला बेचारी हैं ? क्या वह पढ़-लिख कर भी अनपढ़ों का काम कर रही हैं ? क्या बढ़िया खाना बनाकर परोसने और प्रशंसा पाने का हर नारी का मन नहीं होता ? आखिर कब बन जाती है रसोई एक कैद ? प्रस्तुत हैं एक सर्वेक्षण के रोचक तथ्य।

अन्य रचनाएं

अनुभव : 'जब मैंने पहली बार पूरा खाना बनाया'

संस्मरण : जब हम-तुम संग हों किचेन में

सुहागरात : 'इंतजार मैं नहीं, वे कर रहे थे'

फिल्म : मोहसिन खान : क्रिकेट के मैदान से फिल्मी दुनिया की ओर

मनोविज्ञान : आप आशावादी हैं या निराशावादी ?

शिष्टाचार : मना करना सीखिए

कथा साहित्य : लोकप्रिय कथाकार गुलशन नंदा की कहानी 'इंतकाम' प्रभा शर्मा का हास्य-व्यंग्य गुरु-भक्ति और परीक्षा : नये संदर्भ में

मूल्य-६.००

करता है, तो मेरा क्या जाता है?" बहरहाल, दुबे के दरबारी फिर से एक बार राहत की सांस लेकर मुख्यमंत्री निवास के दरबार हाल में पसर कर सुस्ता रहे हैं। क्या सचमुच सांसदों का विद्रोह दुबे के लिए भारी साबित होगा। राजनीतिक पंडित बिहंसकर कहते हैं, "अजी मान-मनुहार का चक्कर है। बाबा-राज अभी खतम नहीं होगा।" विद्रोही सांसदों ने अपनी बैठक में एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री यह पूछते हैं कि चलो दुबे को हटा देते हैं, पर कुछ नाम तो सुझाओ। सांसदों ने मुनादी की थी कि बस नाम सुझाने ही जा रहे हैं। पर नाम सुझाने की बात आते ही विद्रोही तेवर वहीं गलने लगता है और गरमायी हुई राजनीति बर्फ बन जाती है।

हजार दिन। यानी १२ मार्च, १९८५ से ७ दिसंबर, १९८७ तक दुबे सरकार का सफरनामा। पटना के दैनिकों में मोटे-मोटे परिशिष्ट छप रहे हैं, पर हर आम बिहारी निराश है। हजारवें 'बर्थ डे' के मौके पर अखबारों में सरकार की उपलब्धियों के सूखे दावे उन्हें उत्साहित नहीं कर सकते। दुबे सरकार ने उपलब्धियों के चौदह शानदार दावे किये हैं। मसलन, ११८७२९० बिहारीवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का, ३५०९५.५ एकड़ अधिशेष भूमि वितरण का, ११५४ बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का, अनुसूचित जाति के ६,२२,६३७ परिवारों और अनुसूचित जनजाति के ३,१६;७७५ परिवारों को आर्थिक सहायता देने के अलावा अन्य अनगिनत दावे। पर इन दावों की असलियत सोचकर हर आम बिहारी का मन डूबने लगता है।

दुबे के हजार दिन यानी दरमियां, औरंगाबाद, छोटकी छेछानी, अरवल, कंसारा, तौफीर दियारा, कैथी बिगहा जैसे पंचासेक रक्तपातों में बिछी लाशें। हजार दिन माने विकास से कोसों दूर उत्पीड़ित आदिवासियों का झारखंड आंदोलन। हजार दिन यानी लावारिस विश्वविद्यालय, बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था। सच, ये हजार दिन देखते-देखते कैसे निकल गये? १९८८ की चौखट पर खड़ा बिहार देख रहा है—फिर कोई नया अरवल, फिर कोई दूसरा औरंगाबाद!

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

१९८८ में किसान टूटेंगे

१९८७ के आखिरी दिनों में बिहार सरकार की कृषि संबंधी जो नीति रही है, उसका बेहद खतरनाक और मारक असर १९८८ और उसके बाद के कई वर्षों तक बिहार के गरीब किसानों पर पड़ेगा। १९८७ में बाढ़ और कुछ हिस्से में सूखे की समस्या ने पूरे प्रदेश को जर्जर कर दिया है। इसका सबसे अधिक कुप्रभाव खेती पर पड़ा, क्योंकि खरीफ की फसल, जिसका इस राज्य के कुल खाद्यान्न-उत्पादन में बड़ा भाग होता है, में काफी क्षति पहुंची है। सरकारी नजरिये से फसल की क्षति को ५३८ करोड़ के करीब आंका गया है। इस क्षति को पूरा करने के लिए सरकारी मुनादी हुई कि रबी फसल का तकरीबन ७४ लाख टन तक उत्पादन पहुंचाया जायेगा, जबकि आम तौर पर रबी फसल का उत्पादन औसतन ४०-४२ लाख टन प्रदेश में होता रहा है।

इसी सब सोच के तहत बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के सहकारी ढांचे में मजबूती लाकर रबी फसल के उत्पादक को बढ़ाया जाये। जाहिर है, यह कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) के जरिये ही हो सकता था। अभी बिहार में लगभग २५००० 'समितियां' हैं। ये किस हाल में हैं और इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। बहरहाल, इनमें ९००० 'समितियां' आकंठ ऋणग्रस्त थीं कि उन्हें समाप्त करना ही उचित समझा गया। शेष १६००० 'समितियों' को सक्षम बनाने के लिए सबको मिलाकर सात हजार इकाइयों पर ला दिया गया। इन सहकारी समितियों की सदस्यता को कारगर बनाने के लिए समितियों पर लदे १२.५ करोड़ ऋण को पहले सरकार ने चुकाया, क्योंकि बगैर इस ऋण का भुगतान किये कोई भी बड़ा ऋण लेने की हैसियत में ये 'समितियां' नहीं रह गयी थीं।

बहरहाल, अब इन्हीं 'समितियों' के जरिये लघु किसानों को ऋण देने का एलान हुआ। कार्यक्रम के अनुसार इस रबी फसल के लिए ५८७ करोड़ रुपए ऋण के रूप में किसानों को दिया जाना तय हुआ, ताकि वे फसल उत्पादन में इजाफा कर सकें। इस ५८७ करोड़ राशि में 'नाबार्ड' (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) जो देश में ग्रामीण विकास संबंधी बैंक तथा सहकारी संस्थाओं की शीर्षस्थ संस्था है, उससे ३१६ करोड़ रुपए के सहयोग की व्यवस्था हुई। शेष राशि अन्य स्रोतों से एकत्र होना तय हुई। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी कि ५८७ करोड़ रुपए को नगद एवं वस्तु के रूप में ६०:४० के अनुपात में किसानों को दिया जाना है। इसके तहत नीति यह बनी है कि नगद राशि किसानों को तभी प्राप्त होगी जब वे ४० प्रतिशत ऋण खाद आदि के रूप में बिस्कोमान के डीपो से प्राप्त करेंगे। यह बंधन बेशक तकलीफदेह है, क्योंकि बिहार में बिस्कोमान के खाद के बारे में यह किंवदंती रही है कि इसके खाद से फसल बेहतर होने के बजाय जल जाती है या बर्बाद हो जाती है।

बीज का संकट: ऊपरी तौर पर थोड़ी देर के लिए भले ही यह लगे कि यह अभियान रबी के उत्पादन में वृद्धि लायेगा, पर तह में देखने पर रोंगटे खड़े करनेवाले संकेत मिलते हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या बिस्कोमान की खाद और नगद ऋण देने से ही खेती संवर जायेगी। सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं समझी गयी। दूसरी बात कि उन्नत बीज की आवश्यकता जिस मात्रा में होगी, उतनी मात्रा में उचित समय पर किसानों को बीज मिल पायेगा, इसमें संदेह ही है। सरकार अलादीन का चिराग रगड़कर भी उन्नत बीज पैदा नहीं कर सकती। अगर पिछले वर्ष उन्नत बीज की तैयारी नहीं हुई, तो अब दो-तीन गुना उन्नत बीज आसमान से नहीं टपक सकता। बिहार के अखबार में इन दिनों बीज के संकट की रोज-ब-रोज छप रही खबरें इसका खुलासा करती हैं।

बिहार में कृषि के अल्पकालीन ऋण की जो कुल आवश्यकता है, उसे करीब ८०० करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले वर्षों में पंद्रह-बीस करोड़ रुपए से अधिक रबी उत्पादन के लिए कभी ऋण वितरित नहीं किये गये।

इस सिलसिले में जो एक सबसे बेतुकी बात है कि अभी तक खरीफ का उत्पादन लगभग ४० लाख टन होता रहा है। अगर इसे हम मूल्य के रूप में आंकें, तो १५० रुपए प्रति क्विंटल की दर से एक टन की कीमत १५०० रुपए और एक लाख टन की १५ लाख रुपए और ४० लाख टन की ६०० करोड़ रुपए होते हैं। अगर खाद-बीज आदि में खर्च रकम के उत्पादन के कुल मूल्य का बीस प्रतिशत भी माना जाये, तो ५८७ करोड़ रुपए ऋण के रूप में किसानों के द्वारा खर्च किये जाने पर रबी का उत्पादन ५८७ करोड़ रुपए के पांच गुना मूल्य का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में रबी उत्पादन २०० लाख टन इस लिहाज से होना चाहिए जो बिलकुल असंभव है।

कुल मिलाकर लगता यही है कि इतने वृहद स्तर पर किया गया यह कार्यक्रम आखिरकार लूटपाट और ऐतिहासिक घपले की दास्तान बनकर रह जायेगा। बिहार में इतनी मोटी राशि को पचाकर डकार तक न लेनवाली हस्तियों की कमी नहीं। इसलिए ऋण का यह अर्थशास्त्र १९८८ में किसानों को तोड़कर रख देगा, इसमें कोई शक नहीं।

—[illegible]

सरकार और कांग्रेस-इ आमने-सामने

सरकार और संगठन दोनों का तालमेल किसी सरकार को कारगर बनाने के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन राजस्थान में इस समय इंका संगठन और सरकार के बीच ठनी है। ऐसे कौन से हालात वहां पैदा हो गये हैं कि दोनों की आपसी लड़ाई खुलकर सामने आ गयी है और आलाकमान की भी नींद हराम हो रही है?

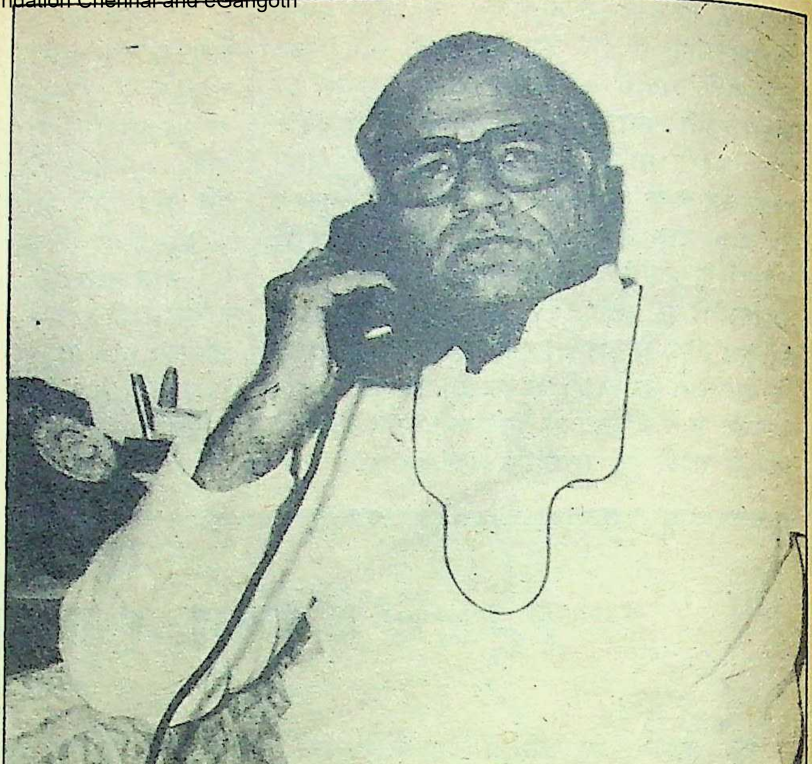

सिंहासन खतरे में: हरिदेव जोशी

श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से कांग्रेस-इ राजनीति का खुलासा करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। श्रीमती गांधी के काम करने और निर्णय लेने के तौर-तरीके वक्त के साथ इतने स्पष्ट हो गये थे कि जिन्हें देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि इंका में किसके दिन फिरने वाले हैं। पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कंप्यूटरीकरण वाली राजनीति स्पष्टता से अस्पष्टता की ओर बढ़ रही है। बहरहाल, उस वक्त की राजनीति की एक विशेषता आज भी बरकरार है और वह है प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी की। कांग्रेस-इ में सफल-असफल सभी नेता वफादारी का राग अलापे बगैर वर्तमान एवं भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते।

राजस्थान में सत्ताधारी दल इस मंत्र का जाप करते हुए कई गुटों में बंटा हुआ है। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपनी कुरसी छिनने से लेकर आज तक इसी मंत्र की ओट में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी पर हमला करते रहे हैं और श्री जोशी इसी मंत्र के साथ उसकी काट करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया भी मंत्र तो यही जपते हैं, पर संजय गांधी के अवसान के समय विलाप और वफादारी का जैसा प्रलाप उन्होंने पेश किया था, उसे आधुनिकता से सराबोर प्रधानमंत्री आज भी नहीं भूलते। उनका दुर्भाग्य है कि श्रीमती मेनका गांधी अमेठी से आगे नहीं बढ़ीं और श्री पहाड़िया को अनुसूचित जातियों के गठबंधन तक सीमित रहना पड़ा।

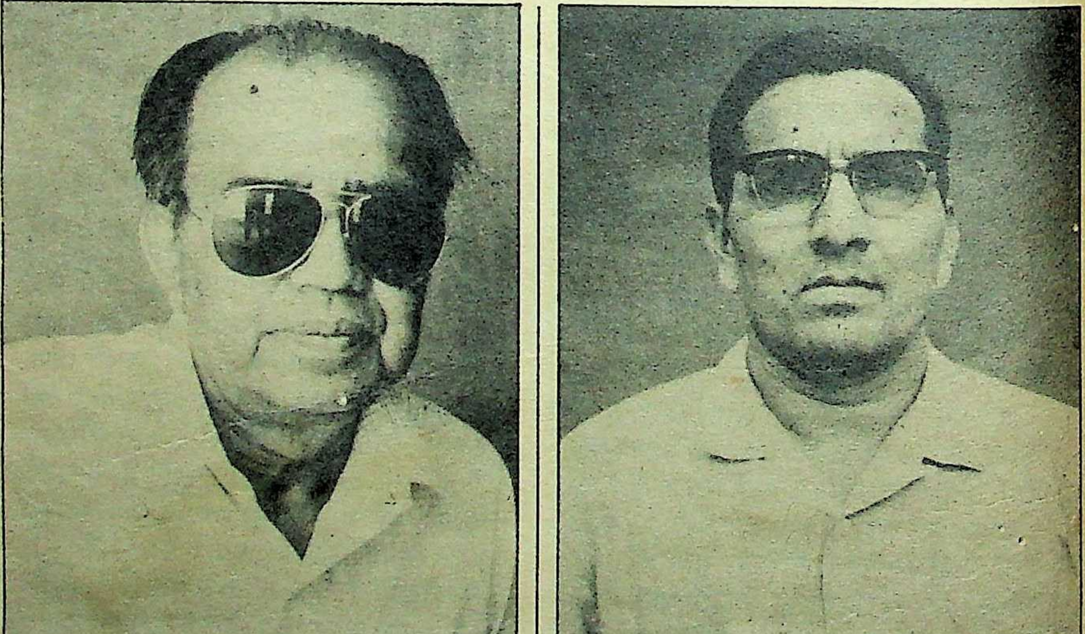

विशेष सलाहकार: मोहन छंगाणी (बायें), पुखराज कालानी

श्री जोशी को पूर्व काबीना मंत्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपनी रणनीति से गाफिल रखा है। इनकी विशेषता यह रही कि भाटी हमलावर होते हुए भी बड़ी शातिरी से अपने को इस आरोप से बचाते रहे। पहली बार जोशीजी की तथाकथित निकम्मी सरकार पर वह तब खुलकर बरसे जब उन्हें अनुमान हो गया कि मुख्यमंत्री जोशी उनके हमले के बाद मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। जब 'माया' ने राजपूत विधायक (कांग्रेस-इ) नरेन्द्र सिंह भाटी से साक्षात्कार लेना चाहा, तो पहले तो वह खुशी-खुशी तैयार हो गये, लेकिन बाद में अपने सलाहकारों की सलाह पर अदृश्य हो गये। 'माया' ने उनसे सम्पर्क साधने का हर सम्भव प्रयत्न किया, पर श्री भाटी ने हर बार

अपने उपलब्ध न होने की बात ही कहलवायी। अपनी बेबाकी से वाहवाही लूटने वाले श्री भाटी 'माया' से साक्षात्कार के लिए क्यों इनकार कर गये? इसकी वजह बड़ी साफ है। श्री भाटी के भामाशाह, जयपुर शहर के कांग्रेस-इ विधायक शिवराम शर्मा उन लोगों में एक थे, जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री जोशी प्रिविलेज मोशन लाने की बात सोच रहे थे। बताया जाता है कि शिवराम शर्मा और पूर्व मंत्री हनुमान प्रभाकर ने विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के (सती) धर्म रक्षा समिति के लोगों से न मिलने के लिए कोई पत्र लिखा था। श्री भाटी का अप्रत्यक्ष रूप से मानना था कि मुख्यमंत्री उक्त पत्र को प्रिविलेज मोशन का आधार बनाने जा रहे थे।

वैसे श्री भाटी ने विधानसभा में अपने भाषण का मुद्दा धर्म रक्षा समिति के नेताओं के उन भाषणों को बनाया था जिनमें प्रधानमंत्री के परिवार का घटिया तरीके से उल्लेख किया गया था। हाई कमान में राजस्थान प्रदेश के मामलों के महामंत्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी मुख्यमंत्री श्री जोशी के प्रति हमदर्दी रखते हुए इस मसले पर उन्हें बचा नहीं सकते थे। बहरहाल, प्रेस के माध्यम से एकतरफा हमलों के बावजूद इन पंक्तियों के लिखे जाने तक श्री जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं।

दरअसल, श्री जोशी दल के उन विधायकों, सांसदों और नेताओं में लोकप्रिय हैं, जिनकी छवि पर हमेशा प्रश्न चिह्न लगा रहा है। मुख्यमंत्री को ऐसी प्रशंसा विपक्ष के उन नेताओं से भी हासिल हुई है, जो राजनीति को शतरंज की तरह खेलते अथवा अपनाते हैं। इसके विपरीत यथास्थिति से परे हट कर सोचने वालों में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का इसी अनुपात में ह्रास हुआ है। उनके 'व्यावहारिक मुख्यमंत्री' बनने के प्रयास ने दल की घोषणाओं

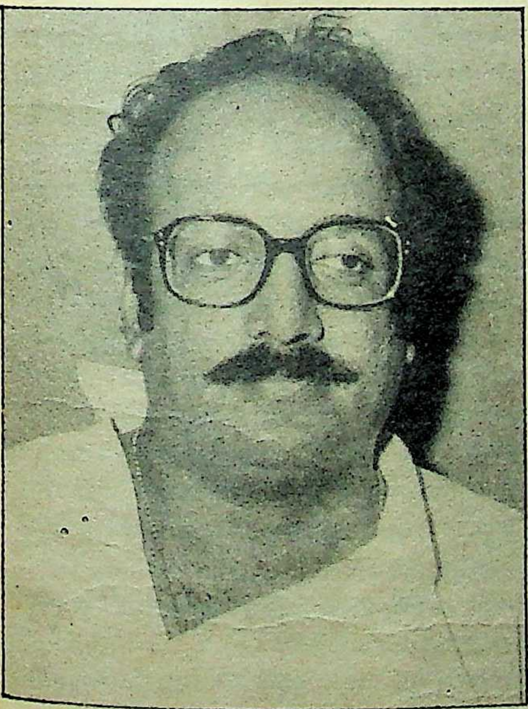

चालाकी से हमला : नरेंद्र सिंह भाटी

साक्षात्कार/हरिदेव जोशी

मेरे पास सबके कामों का हिसाब है

विवादास्पद बनते जा रहे मुख्यमंत्री जोशी से जब 'माया' ने प्रधानमंत्री को दिये गये ज्ञापन पर प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उनका कहना था, "सारा झगड़ा जोधपुर में पीने के पानी की कमी का है। उसके लिए हमने इंदिरा गांधी नहर से पानी लाने की योजना को गति दे दी है। फिर आज भी हमारे यहां स्थिति सूखे के बावजूद गुजरात की तरह नहीं बिगड़ी है। प्राइममिनिस्टर क्या कोई नासमझ आदमी हैं? क्या वह नहीं जानते कि यह राजस्थान कैसे चल रहा है? जो हालात मद्रास में पैदा हो गये थे, वे राजस्थान में नहीं हुए। इन हालात के बावजूद हम विकास की गति को बनाये हुए हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि राजस्थान की समस्याएं क्या हैं। वह यह भी जानते हैं कि सालों पहले उपजी समस्याओं का समाधान हरिदेव जोशी ने ही किया है।" मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद 'माया' ने विषय से संबंधित कुछ और सवाल किये। प्रस्तुत हैं, बातचीत के कुछ अंश:

माया : नरेशचंद्र चतुर्वेदी ने बयानों में आपकी तारीफ की है, पर सुना है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कुछ और दी है?

जोशी : इसका अर्थ यह हुआ कि चतुर्वेदीजी बहुत झूठे आदमी हैं। वह सार्वजनिक रूप से एक बात कहते हैं और वहां जाकर दूसरी बात कहते हैं।

माया : प्रदेश कांग्रेस के मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने आपके विपक्ष से रिश्तों की जब प्रधानमंत्री से बात कही, तो उन्होंने कुछ करने का आश्वासन दिया है?

जोशी : कोई टिप्पणी नहीं।

माया : प्रधानमंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अथवा सरकार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इसकी कोई सूचना आपको है?

जोशी : देखिए, अगर कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, तो मुझसे बात जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे बताये बगैर कुछ किया जायेगा। हाल में जब मैं मिला, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वह मुझसे नाराज हैं। एक बात मैं आपसे पूछता हूं। जब पिछली बार प्रधानमंत्री यहां आये थे, तो प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भाषण दिया था। आपको याद होगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे भवन-विस्तार के लिए शिलान्यास करवाया था। उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री इस विस्तार के लिए डेढ़ लाख रुपया अभी दे रहे हैं और इतना ही बाद में देंगे। तब प्रधानमंत्रीजी का भाषण क्या था? उनका कहना था एक वर्ष तक कोई भवन नहीं बनेगा। जोशीजी यह डेढ़ लाख रुपया आप मुझे दीजिए। चैक मैंने उनको दे दिया था। प्रधानमंत्री का कहना था दूसरी किस्त भी आप मुझे ही देंगे। प्रधानमंत्री ने उसी प्रदेश संगठन को अकाल राहत कमेटी के रूप में बदल दिया था। साथ ही कहा था कि हममें आपस में मतभेद हैं, पर एक साल सब भुला दो। जब अच्छी बरसात होगी, हालात अच्छे होंगे तब मतभेद देखेंगे—लड़ लेंगे।

माया : मोहन छंगाणी और पुखराज कालानी के खौफ का जिक्र ज्ञापन में है। कहा गया है कि इनसे मंत्रिमंडल के सदस्य भी घबराते हैं।

जोशी : वे कुछ भी कह दें। क्या करते हैं छंगाणी? मुझसे मिलने हर पक्ष के लोग आते हैं। मेरे पास सबके कामों का हिसाब है। आप देख लीजिए कामों के लिए कौन सबसे ज्यादा कहता है।

माया : पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने आपको विधानसभा में ललकारा। आलाकमान इस संबंध में क्या करने जा रहा है?

जोशी : नो कोमेंट (कोई टिप्पणी नहीं)।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/राजेन्द्र चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस-इ संगठन मंत्री

'हमारा काम मुख्यमंत्री बनाना या हटाना नहीं है'

प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राजेन्द्र चौधरी जोधपुर संभाग के ऐसे विधायक हैं, जिन्हें विपक्षी लहर के बावजूद जाट बहुल क्षेत्र में विजय हासिल हुई थी। उल्लेखनीय है कि भरतपुर में राजा मानसिंह की हत्या का जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को मानते हुए मतदाताओं ने कांग्रेस-इ के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को पराजित किया था। मुख्यमंत्री जोशी के विरुद्ध प्रदेश संगठन के प्रतिनिधि के रूप में उनका सक्रिय होना अर्थ रखता है। प्रस्तुत हैं, उनसे सरकार और संगठन में उत्पन्न हुए विवाद को लेकर हुई बातचीत के कुछ अंश:

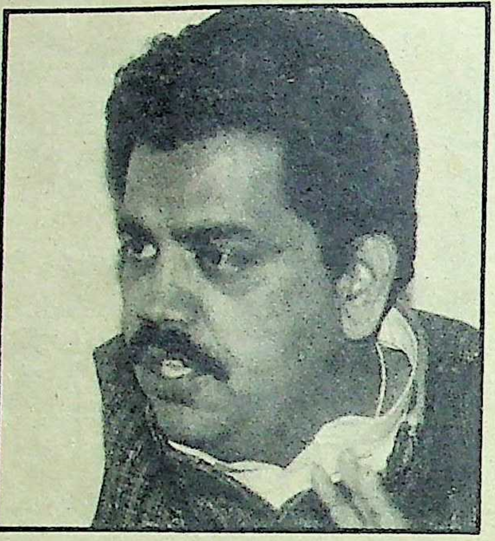

माया : मुख्यमंत्री जोशी से अचानक आपकी नाराजगी की क्या वजह है ?

चौधरी : नाराजगी अचानक नहीं है। नाराजगी मुख्यमंत्री और उनके काम करने के तरीके को लेकर है, जिसे हमने लम्बे समय से महसूस किया है। यही वजह है कि हम मानने लगे हैं कि हमारे नेता एवं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की इच्छाओं के अनुरूप श्री जोशी सरकार नहीं चला रहे।

माया : कोई उदाहरण दे सकेंगे आप ?

चौधरी : बिलकुल, जब श्री जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आयी थी, तो हमने उनके अनुभव को देखते हुए उनका समर्थन किया था। हम समझते थे कि इससे हम कांग्रेस-इ को प्रदेश में मजबूत बना पायेंगे, पर पश्चिमी राजस्थान में जहां कांग्रेस ने अपना आधार खो दिया था, जोशीजी ने उलटा ही रास्ता अख्तियार किया। उस क्षेत्र में मुख्यमंत्रीजी ने जिन्हें अपने सलाहकार बनाये हैं, वे ऐसे लोग हैं जो संकट के समय पार्टी छोड़कर सत्ता के तलुवे चाटने लगे थे। इन लोगों ने जैसे बयान दिये थे, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि फलौदी से निर्वाचित निर्दलीय उम्मीदवार मोहन छंगाणी ने जनता पार्टी के शासन में आने पर इंदिराजी के संबंध में क्या कहा था। इसी तरह सोजत के पूर्व विधायक पुखराज कालानी हैं। १९७७ में कांग्रेस छोड़ जनता पार्टी में जा मिले थे। आज भी क्षेत्र में वह श्री जोशी के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और व्यक्तिगत सम्बन्ध तो हैं ही। उधर लोकदल-ब के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा से इनकी दोस्ती हमारे संगठन के लिए भारी पड़ रही है। जोधपुर संभाग में लोकदल के हितों का विशेष खयाल रखा जा रहा है और इस वजह पर रखा जा रहा है कि श्री मिर्धा विधानसभा में जोशीजी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हैं, जबकि वह केन्द्र सरकार और राजीवजी को आड़े हाथों लेते हैं।

माया : पाली जिले में सांप्रदायिक दंगों एवं सामंती अत्याचारों के लिए आप जोशीजी को अपने ज्ञापन में किस तरह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ?

चौधरी : सोजत से कांग्रेस-इ के विधायक माधव सिंह दीवान १९७७ से विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। इलाके की रग-रग से वह वाकिफ हैं। पाली से निर्वाचित भाजपा की विधायक कुमारी पुष्पा जैन और विपक्ष के नेता भैरोसिंह शेखावत ने जब साधू हत्या को साम्प्रदायिक रूप देने की चेष्टा की, तो वह मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहते थे। पर मुख्यमंत्री के निजी सचिव से आगे बात बढ़ी ही नहीं। मुख्यमंत्री मिलने का वक्त देने से कतराते रहे। मजबूरन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत को सारा षड्यन्त्र समझाया। साण्डेराव-मोंणिहारां में सामंती अत्याचारों पर भी मुख्यमंत्री इसी तरह आंख बंद किये देखते रहे। मुख्यमंत्री ने सोजत वाले मामले में दो मंत्रियों श्रीमती कमला और हीरालाल देवपुरा को भेजा, पर उन लोगो ने श्री दीवान को बात करने के लिए आमंत्रित तक नहीं किया। विपक्ष के नेताओं को तूल देकर अपने ही दल के विधायकों को गौण करने के बाद हम मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में क्या राय बनायेंगे ? ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में भी मुख्यमंत्री ने उस क्षेत्र में जाना उचित नहीं समझा। जो कुछ किया, वह अपने सलाहकार पुखराज कालानी के माध्यम से किया।

माया : यानी मुख्यमंत्री को आप विपक्ष से मिला हुआ और प्रशासकीय दृष्टि से असफल मानते हैं ?

चौधरी : हम जो मानने लगे हैं उसके प्रमाण हैं। यह मात्र आरोप नहीं है। सती प्रकरण में मुख्यमंत्री ने क्या किया ? वह तब सक्रिय हुए जब प्रधानमंत्री ने सती कांड की निन्दा की और उन्हें हिदायत देते हुए पत्र लिखा।

माया : सती प्रकरण में तो प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष पर भी आपके साथी विधायक साथी नरेन्द्र सिंह भाटी आरोप लगा रहे हैं ?

चौधरी : यह गलत है। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में हमने इसकी निन्दा की है। मैंने स्वयं यह जिम्मेदारी निभायी थी।

माया : प्रधानमंत्री से हाल की मुलाकात में क्या आपने मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही है ?

चौधरी : हमारा काम मुख्यमंत्री बनाना या हटाना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रधानमंत्री को राज्य में कांग्रेस संगठन और सरकार की स्थिति से अवगत करायें। हमने यही किया है। यह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वह स्थितियां देख-सुनकर मुख्यमंत्री बदलते हैं या नहीं।

माया : आपके ज्ञापन के अनुसार मुख्यमंत्री गलत हैं, जबकि महामंत्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी मुख्यमंत्री को सफल होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं।

चौधरी : उनके अखबारी बयान बदलते रहते हैं। हमने इस सम्बन्ध में उनसे बात की है। इसी का नतीजा था कि राज्य में विधायकों से बात करने के लिए बाद में मुख्यमंत्री निवास के बजाय खास कोठी तय की गयी। हमने, विशेष रूप से मैंने उन्हें स्पष्ट कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं और उसमें भी मैं श्री राजीव गांधी के साथ हूं। हम हरिदेव जोशी "व्यक्ति" के खिलाफ नहीं हैं। हम तो उनकी कार्य प्रणाली को गलत मानते हैं। आलोचना के बाद उसमें सुधार होना चाहिए, वह नहीं हुआ। दिल्ली में हमने चतुर्वेदीजी से अखबारों में छपे बयान के संबंध में बात की है। हमने बताया कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ दस बारह लोगों के होने की बात कहते हैं। आप चाहें तो हम इस संख्या से दस गुना ज्यादा विधायकों से हस्ताक्षर करवाकर पेश कर सकते हैं ? दरअसल, हमारे लिये मामला शक्ति परीक्षण का नहीं है। हम तो अपने दल को जनप्रिय बनाने और प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप सरकार को काम करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं।

माया : आपने प्रधानमंत्री को श्री चतुर्वेदी के रवैये से अवगत कराया ?

चौधरी : हां, हमने कहा चतुर्वेदीजी राजस्थान आये और मुख्यमंत्रीजी के निवास पर मंत्रियों के दबाव पर विधायकों को मिलवाया गया। इस पर प्रधानमंत्रीजी का कहना था, "हां, इसकी मुझे जानकारी मिल गयी है और हम दिखवा रहे हैं, कुछ करेंगे।" हमें प्रधानमंत्री से मिलकर काफी सकून मिला है। हमारी दिलचस्पी जोशीजी को हटाने अथवा रखने में नहीं है। हमें तो अपने नेता को बात कहनी थी सो कह दी।

—ओम सैनी

वादों और इरादों को गौण कर दिया है। जन प्रतिनिधियों से ज्यादा रुतबा नौकरशाहों को हासिल हुआ है। ऐसा सोच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस-इ संगठन अध्यक्ष एवं सांसद अशोक गहलोत एवं उनके सहयोगियों का रहा है।

प्रधानमंत्री को ज्ञापन: मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री के इन 'विशेष अनुयायियों' का हमला पहले कभी संयुक्त रूप से नहीं हुआ। पर इस बार २४ नवंबर, १९८७ को प्रदेश कांग्रेस-इ संगठन के मंत्री एवं युवा विधायक राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में चार विधायक प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मिले। राजेन्द्र चौधरी जोधपुर डिवीजन के बिलाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव में लोकदल-ब के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा के दामाद को उस वक्त हराया था, जब जोधपुर डिवीजन में विपक्ष की लहर चल रही थी। प्रधानमंत्री से मिलने वाले अन्य विधायकों में कांग्रेस-इ के चार ऐसे विधायक शामिल थे जो प्रधानमंत्री की मनःस्थिति को प्रभावित करते हैं। मसलन, एयरफोर्स से स्वाड्रनलीडर का पद छोड़ कांग्रेस-इ विधायक बने लक्ष्मण सिंह तथा इंजीनियरिंग डिग्रीधारी माधोसिंह दीवान शामिल थे। अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयनारायण बैरवा और महिला विधायक कमला भील साथ थे। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर उन्होंने जोशी सरकार के खिलाफ संगठन की ओर से पहला हमला किया। स्वयं प्रधानमंत्री ज्ञापन स्वीकार करते हुए इस वास्तविकता से अवगत थे कि यह लोग सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत के प्रतिनिधि हैं।

ज्ञापन में इन लोगों ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह विपक्ष के ऐसे नेताओं से मित्रता किये बैठे हैं जो मुख्यमंत्री की तो प्रशंसा करते हैं, पर प्रधानमंत्री के कटु आलोचक हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने फलौदी क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय विधायक मोहन छंगाणी और पाली के पूर्व कांग्रेसी विधायक पुखराज कालानी को अपना विशेष सलाहकार बना रखा है, जबकि ये लोग जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस-इ को बदनाम करने में सबसे आगे रहे हैं। प्रशासन और मंत्रियों के निकम्मेपन की चर्चा के साथ ज्ञापन में एक ऐसी रिपोर्ट का उल्लेख है जिसकी खोजबीन विधानसभा की जनसमिति के सदस्य होने के नाते स्वयं राजेन्द्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह ने की है।

जनलेखा समिति की इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के जलदाय विभाग द्वारा पिछले पांच साल में पाइपों की खरीद में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। जनलेखा समिति ने जलदाय विभाग द्वारा जांच में पूर्ण सहयोग न देने के बावजूद छह माह की मशक्कत के बाद राज्य के उद्योग सचिव, जलदाय विभाग के सचिव, मुख्य अभियन्ता, जलप्रदाय एवं सीवरेज बोर्ड के तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सदस्य को घोटाले में लिप्त होने का दोषी करार दिया है। इस समिति ने विशेष रूप से इस बात की जांच की कि क्या विभाग ने १९८२-८३ से ८६-८७ तक बगैर आवश्यकता के भी पाइप खरीदा? अथवा उसका मूल्य बाजार में उपलब्ध मूल्य से ज्यादा दिया? और क्या रिंगों की खरीद में तीस करोड़ रुपए का नुकसान हुआ?

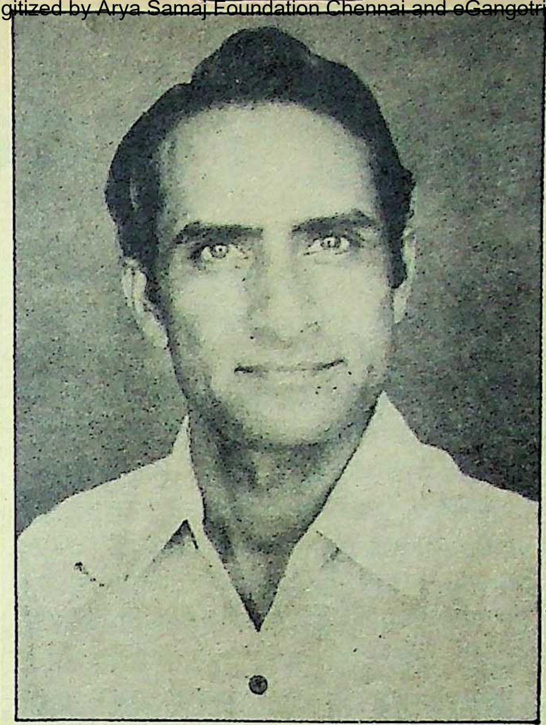

सरकार का भंडाफोड़: लक्ष्मण सिंह

पहले सवाल के जवाब में समिति को विभाग के मुख्य अभियंता ने केवल एक साल की खरीद की सूचना दी। यह खरीद बिना ज़रूरत के 'सस्पेंस' खाते में सवा छह करोड़ की की गयी। समिति को इस तरह से तीन स्थानों की खरीद का पता चला जिसमें १३५ करोड़ रुपए के पाइप खरीदे जाने का पता चला। समिति ने अपने दूसरे सवाल की खोज में पाया कि भीलवाड़ा की श्री पाइप्स लिमिटेड के पाइप खरीद कर विभाग ने इस फर्म को ३.६० करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। समिति को जांच के दौरान पता चला कि इस फर्म से बिना निविदा के दो वर्षों में बीस करोड़ रुपए मूल्य का पाइप ऊंची दरों पर खरीदा गया, जबकि अन्य कम्पनियां कम दामों पर पाइप बेचने के लिए आवेदन करती रहीं। एक रोचक तथ्य यह भी सामने आया कि उक्त फर्म इसी दौरान बाहर के संस्थानों को कम दामों पर पाइप बेंचती रही। यह तब हुआ जब, कि इस फर्म में राजस्थान सरकार के 'रीको' विभाग का कुछ पैसा लगा था। समिति ने पाया कि विभाग द्वारा ३४ रिंगों की खरीद के समय निविदाओं में न्यूनतम दरों को गौण कर दिया गया। जिस फर्म ने कम दर पर रिंग सप्लाई करने की पेशकश की थी, उसकी निविदा बहाना बना कर रद्द कर दी गयी। रोचक तथ्य यह भी उजागर हुआ कि रिंग सप्लाई करने वाली फर्मों के एजेन्टों को कमीशन रिंगों की जांच से पहले ही अदा कर दिया गया।

समिति ने इन मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तीन माह की अवधि में कठोरतम कार्रवाई के निर्देश देते हुए श्री पाइप्स लिमिटेड, भीलवाड़ा से नाजायज कमाया पैसा वसूलने की बात कही है। २८ अक्तूबर को विधानसभा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट को राजेन्द्र चौधरी ने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के नमूने के रूप में प्रधानमंत्री को पेश किया है।

यह पहला मौका है जबकि प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखित रूप में कोई ज्ञापन प्रधानमंत्री को पेश किया है। वैसे इससे पूर्व मंत्री पद प्राप्त न होने से उपजी निराशा के फलस्वरूप सत्ताधारी दल के विभिन्न गुट श्री जोशी के विरुद्ध ज्ञापन देते रहे हैं, पर उन पर आलाकमान ने गौर नहीं किया। राजेन्द्र चौधरी ने नरेशचंद्र चतुर्वेदी की कार्य शैली के प्रति भी प्रधानमंत्री से शिकायत की। उनका कहना था कि श्री चतुर्वेदी मुख्यमंत्री के मेहमान बनकर उन्हें 'अनुभवी' एवं 'बेहतर' मुख्यमंत्री होने का खिताब सार्वजनिक रूप से देते आये हैं। उनका रवैया वस्तुस्थिति को आलाकमान से छिपाने जैसा रहा है।

इसके बाद से प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 'राजनीतिक हालात' समझने-जानने की जिम्मेदारी गृहमंत्री बूटा सिंह को सौंपी है। इसी के साथ संगठन के लोग गृहमत्रों से मिलकर यह पंक्तियां लिखे जाने तक राज्य की उन समस्याओं से अवगत करा रहे थे जिनके लिए वे सरकार एवं प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का अध्यादेश जारी कर ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिससे जिला प्रमुख और प्रधानों को हटाकर इन संस्थाओं पर अफसरशाही का वर्चस्व स्थापित हो जाये। अब देखना यह है कि १८ दिसंबर को प्रधानमंत्री राजस्थान के सरिस्का टाइगर डैन में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक करोड़ की लागत से आयोजित होने वाली बैठक में राजस्थान सरकार और संगठन के बारे में क्या फैसला लेते हैं?

यह पहला मौका है जबकि प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखित रूप में कोई ज्ञापन प्रधानमंत्री को पेश किया है। वैसे इससे पूर्व मंत्री पद प्राप्त न होने से उपजी निराशा के फलस्वरूप सत्ताधारी दल के विभिन्न गुट श्री जोशी के विरुद्ध ज्ञापन देते रहे हैं, पर उन पर आलाकमान ने गौर नहीं किया। राजेंद्र चौधरी ने नरेशचंद्र चतुर्वेदी की कार्य शैली के प्रति भी प्रधानमंत्री से शिकायत की।

जनप्रतिनिधिविहीन नगरमहापालिकाएं

लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में ही चरमराहट

इलाहाबाद उच्चन्यायालय की लखनऊ पीठ पे आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार १९७० से टाले जा रहे नगरमहापालिकाओं के चुनाव २९ दिसम्बर १९८७ तक कराने के लिए बाध्य है, लेकिन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह सूखे की समस्या का बहाना बनाकर इन चुनावों को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

"तेरे वादे पर जिये हम, तो ये जान झूठ जाना,
कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता।"

उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु के ११८ साल बाद कोई जज अपने फैसले में उनके इस शेर को शामिल करते हुए वर्तमान सरकार को वादाखिलाफी का अहसास करायेगा। इस शेर का उद्धरण के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज न्यामूर्ति-द्वय सगीर अहमद और एस०सी० माथुर ने १४ मई, १९८७ के उस फैसले में प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को २९ दिसम्बर, १९८७ तक सभी महापालिकाओं के चुनाव करा लेने का निर्देश दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार जब निहित स्वार्थ के कारण स्थानीय निकाय के चुनाव लगातार टालने लगी, तो लखनऊ के एक वकील सीताराम द्विवेदी ने उच्च न्यायालय की शरण ली। श्री द्विवेदी इस समय लोकदल-अ के लीगल सेल (प्रकोष्ठ) के संयोजक हैं। उन्होंने २ दिसम्बर, १९८६ को इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर करते हुए प्रार्थना की थी कि वह उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्तशासन सचिव और स्थानीय निकाय के निदेशक को आदेश या निर्देश दे कि वे उचित समयावधि में नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया का चुनाव करायें।

याचिका में चुनाव कराने की आवश्यकता

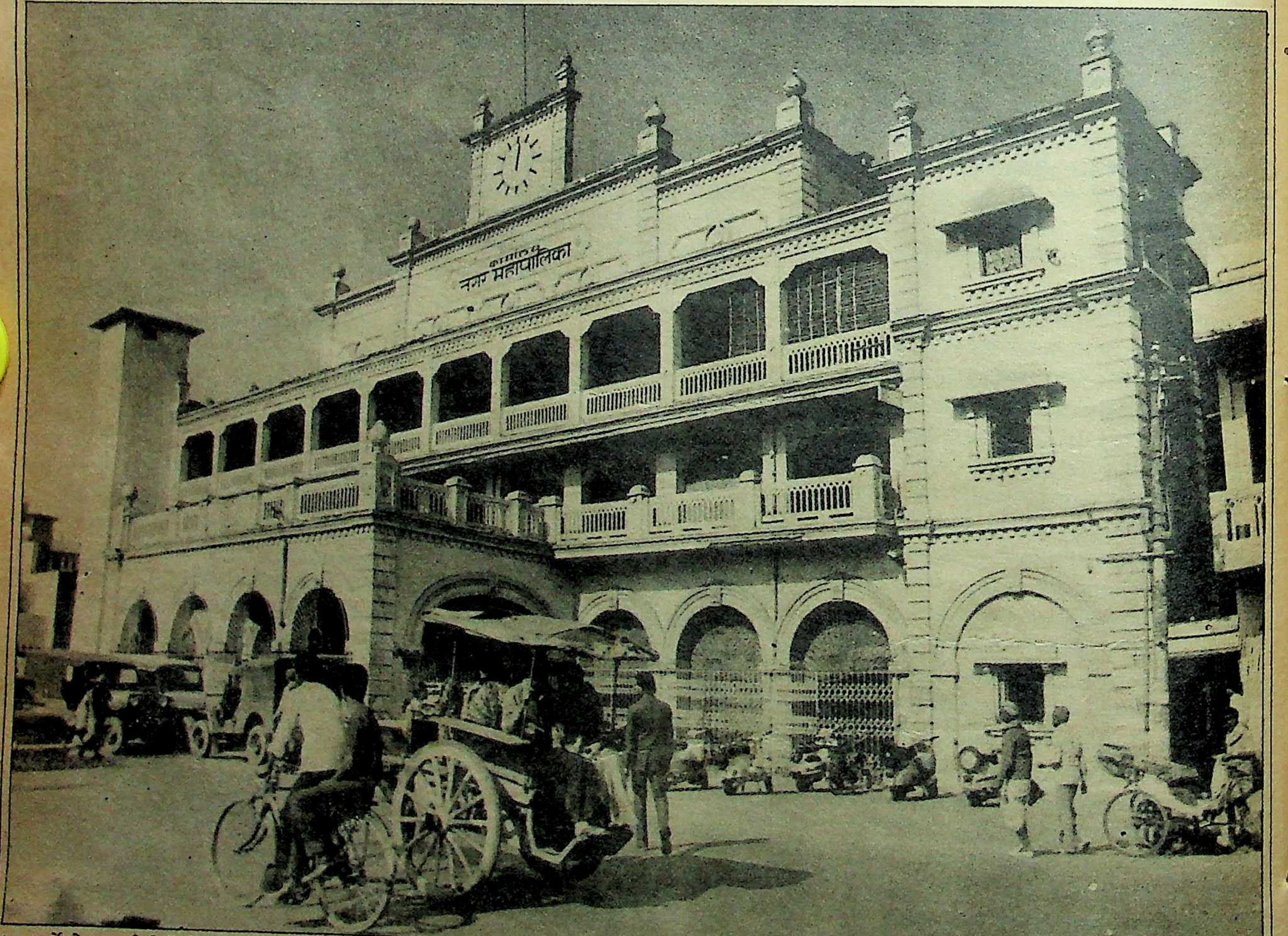

१७ वर्षों से जनप्रतिनिधिविहीन : लखनऊ नगरपहापालिका का कार्यालय

छाया : गजेंद्र कुमार

पर बल देने के लिए श्री द्विवेदी ने दस कानूनी आधार बताये थे। इनमें से एक था—जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायों में सरकार और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जबकि संविधान के तहत महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव निर्धारित समय पर कराना और स्थानीय निकायों का विधिवत गठन करना लाजिमी है। याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव न कराकर सरकार भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध काम कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर महापालिका और नगरपालिका अधिनियम तथा टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया अधिनियम में सरकार बार-बार संशोधन करके कोई-न-कोई बहाना बनाकर १९७० से इन चुनावों को लगातार टालती आ रही है। चूंकि इन संशोधनों के कारण उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने और मतदाता मत देने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं, इसलिए ये सभी संशोधन असंवैधानिक और अवैध हैं।

याचिता और सरकारी वकील की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश-द्वय ने अपने फैसले में एक स्थान पर लिखा— "चूंकि हर नाटक का एक अंत होता है, इसलिए टूटे वादों की अनेक घटनाओं वाले इस नाटक का भी न्यायशक्ति के माध्यम से शीघ्र अंत होना चाहिए।"

वादे-दर-वादे : बात भी सही है। १९७० से लगातार २५ बार वादा करने के बाद भी सरकार ने महापालिका के चुनाव नहीं कराये। इस दौरान आधा दर्जन स्वायत्तशासन मंत्रियों ने कई बार विधानसभा और उसके बाहर चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन जिन मंत्रियों ने ऐसी घोषणा या वादे किये, वे या तो घोषणा के बाद मंत्रिपरिषद से निकाल दिये गये या फिर उनका विभाग बदल दिया गया। ऐसा हादसा कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों के शासनकाल में उनके मंत्रियों के साथ हुआ है। इनमें जगदीश शरण अग्रवाल, श्रीकृष्ण गोयल और रामसिंह खन्ना—कांग्रेस के थे, जबकि तीन अन्य सत्यप्रकाश मालवीय, गणेशदत्त बाजपेयी और रामाधार पाण्डेय जनता पार्टी की सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री थे। अब तो हटाये जाने या विभाग छिन जाने के 'अपशकुन' के डर से वर्तमान नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती पद्मा सेठ ऐसा वादा करके फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहतीं। १९७० से अब तक छह मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, शायद यही वजह है कि इस साल के शुरू में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने वाराणसी में स्पष्ट कह दिया था कि फिलहाल महापालिकाओं के चुनाव कराने सम्भव नहीं हैं।

सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि नगर महापालिकाओं के चुनाव कराने के बदले उन पर प्रशासक थोपने की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने की थी और आज वह और उनकी पार्टी महापालिका के चुनाव न कराने के लिए सत्तारूढ़ दल को कोस रही हैं। यही नहीं, चुनाव कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट भी लोकदल के विभाजन के पूर्व बहुगुणा जी के ही साथ थे। चुनाव न कराने के लिए इंका की आलोचना करने वाला विपक्ष भी सत्ता में आने के बाद चुनाव कराने की हिम्मत नहीं बटोर सका। वह उसी तरह भयभीत था, जिस तरह आज इंका है।

दरअसल, सत्ता में आनेवाली राजनीतिक पार्टियां छोटे-छोटे इलाकों में चुनाव कराकर अपने दलों में फूट का जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं, भले ही इसके लिए नगरीयं इलाके में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को ही क्यों न तोड़ देना पड़े। इस बारे में एडवोकेट वाई०एस० लोहित और लखनऊ के भूतपूर्व मेयर मदन मोहन सिंह सिद्धू का कहना है, "हम सोच, अमल, और तेवर में लोकतांत्रिक नहीं हैं। हम प्रजातांत्रिक संस्कृति को मन से अपनाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इसीलिए सत्ता में आने पर हर राजनीतिक पार्टी के नेता मोहल्ले के चुनाव में मतदाताओं के गुस्से को झेल पाने से घबड़ाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भाग लेना हमारी मजबूरी है।"

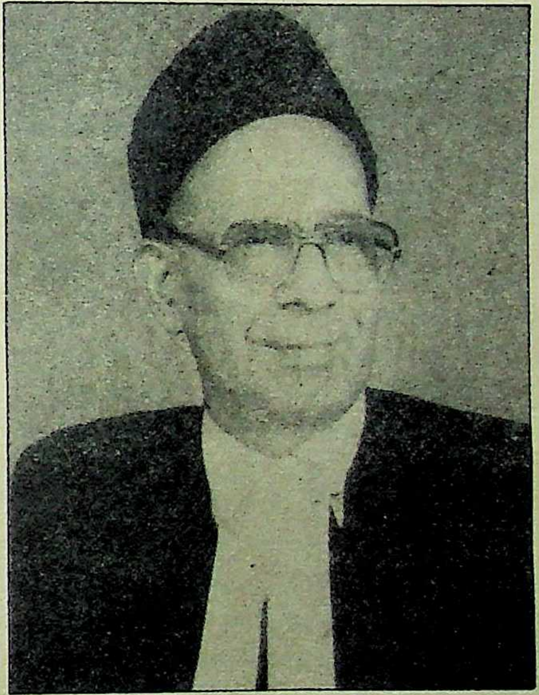

उच्चन्यायालय में दस्तक : अधिवक्ता सीताराम द्विवेदी

डाक्टर सिद्धू का तर्क है कि पहले महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के दौरान भी बम्बई नगर महापालिका के चुनाव हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत नें भी इन असाधारण परिस्थितियों में भी चुनाव को नहीं टाला था, जबकि हमने उसी बम्बई महापालिका के चुनाव को आजादी के बाद बहाना बनाकर टाल दिया। यही रवैया उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के साथ यहां की सरकार अपना रही है।

उत्तर प्रदेश में आठ नगर महापालिकाएं हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा की नगर महापालिकाएं पुरानी हैं। गोरखपुर, मेरठ और बरेली की महापालिकाओं का गठन प्रशासकों की नियुक्ति के बाद किया गया है और ये तीनों अपने जन्मं से ही प्रतिनिधि-विहीन हैं। आठों महापालिकाओं के कामकाज की देख-रेख आई०ए०एस० अधिकारी प्रशासक की हैसियत से करते हैं। ये प्रशासक जहां आम नागरिकों की पहुंच से दूर हैं, वहीं बाबुओं के रहमो-करम पर नागरिक सुविधाओं का तामझाम खरामा-खरामा चल रहा है। नौकरशाही और बाबूशाही अपने कामों के लिए सिर्फ अपने विभाग के मुखिया या मंत्री के प्रति ही जवाबदेह हैं। नतीजे के तौर पर भवन कर लगाने, चुंगी दरों में वृद्धि करने—जैसे बड़े और जिम्मेदारी वाले कामों में नौकरशाहों की मनमानी हर सीमा को पार कर गयी है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यह कैसी विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी शहरी आबादी, अफसरशाही के सामन्ती रवैये को मजबूरी में झेल रही है!

केवल आठ महापालिकाओं के ही सीमा क्षेत्र में ५५ लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो लोकसभा के आठ सदस्यों और विधान सभा के ३० सदस्यों को तो चुनते आ रहे हैं, लेकिन नौकरशाही के बढ़ते दवाब, सत्ताधारी दल के सांसद व विधायकों के प्रभाव और राजनीति नेतृत्व की भय-संस्कृति की वजह से ये ५५ लाख मतदाता महापालिकाओं के जनप्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से पिछले १७ वर्षों से वंचित हैं।

हमारे तेवर लोकतांत्रिक नहीं : अधिवक्ता वाई०एस० लोहित

नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया की हालत तो और बदतर है। पूरे प्रदेश में २२१ नगरपालिकाएं, ४२१ टाउन एरिया और २० नोटीफाइड एरिया हैं। नगरपालिकाओं में चुने हुए सदस्यों की संख्या करीब पांच हजार होती है, जिनकी कुरसियों पर डेढ़ दशक से धूल जमी हुई है। इसी तरह टाउन एरिया में पहुंचने का स्वप्न देखते-देखते चार हजार, आठ सौ जनप्रतिनिधि पिछले १७ वर्षों में शरीर से शिथिल हो चुके हैं।

कब्र खुदवाने का डर : लगभग ११ हजार जन प्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय के प्रतिनिधित्व से वंचित रखने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इतनी संख्या में उम्मीदवारों का चयन करना अब न तो सत्ताधारी दल के बस की बात है और न ही विपक्ष इस मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है। दरअसल, तदर्थवाद और मनोनयन पर चल रहे राजनीतिक संगठनों के नेता गुटबाजी से ग्रस्त ग्रासरूट (निचली) इकाइयों से उम्मीदवार चुनकर अपनी कब्र नहीं खोदना चाहते हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश इंका के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं, "जब संगठन के अन्दर ही लोकतंत्र कायम नहीं है, तो शहरी लोकतंत्र को कायम करने की हिम्मत हम कैसे कर सकते हैं?"

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तेजनारायण गुप्त इस सचाई को कुछ इस तरह बयान करते हैं, "सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष की शहरी लोकतंत्र के बारे में मौखिक सहानुभूति है। हर दल का नेता अपने चमचों को विधायक और सांसद बनवाने की जी-तोड़ कोशिश करता है। अगर स्थानीय निकायों में चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, तो नेताओं को लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनावों में अपने 'बगल बच्चों' (चमचों) को जितवाने के लिए बड़े नेताओं की खुशामद करनी पड़ेगी। ऐसी हालत में नेता का अहं आम कार्यकर्ताओं की ज़िरौरी को गवारा नहीं कर सकता। यही वजह है कि निकायों के चुनाव में किसी दल की कोई दिलचस्पी नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि मोहल्ले के प्रतिनिधि तक इलाके का मतदाता आसानी से पहुंच जाता है और अपना काम करवा लेता है। इनकी अनुपस्थिति

नियम और कायदे की किसे परवाह है?

शहरी लोकतांत्रिक आंदोलन से शुरू से जुड़े सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता अफसरशाही में फंसी महापालिकाओं की कार्यप्रणाली के बारे में एक राय हैं। उनका विचार है कि महापालिकाओं के चुनाव न कराने से सरकारी अमले को इतनी ताकत मिल गयी है कि वह अब न तो नियमों की परवाह करता है और न कायदे-कानून की।

जनता पार्टी के डाक्टर एम०एम०एस० सिद्धू, भारतीय जनता पार्टी के लालजी टण्डन और इंका के शाहिद हुसैन रिजवी का आरोप है, "आम जनता नागरिक सुविधाओ के लिए अफसरों के मुंह जोहती है और दोनों के बीच 'बाबू की दीवार' खड़ी है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब लिहाज और रसूक की जगह पैसे ने ले ली है। अफसरों के इस अभेद्य किले को तोड़ने का अब एक मात्र उपाय चुनाव के जरिये जनप्रतिनिधियों का स्थानीय निकायों में पहुंचना है। हमारे जमाने में भी बाबू और अफसर थे, मगर उन्हें हमने कभी 'हावी' नहीं होने दिया और उनकी मनमानी पर हमेशा अंकुश रखा, क्योंकि हमें हर दिन अपने काम के लिए मोहल्ले को जवाब देना पड़ता था।"

डाक्टर सिद्धू तो लखनऊ नगर महापालिका के कई साल तक 'एल्डरमैन' रहे हैं। वह दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सगे मामा कैलाशनाथ कौल को हराकर मेयर बने थे। लालजी टण्डन लखनऊ की धनी और घनी आबादी 'चौक' से नगर महापालिका के १९६० से लेकर १९७३ तक सभासद रहे हैं। इंका के मुखर और असरदार सभासद शाहिद हुसैन रिजवी ने १९६८ से लेकर १९७३ तक अपने इलाके अमीनाबांद की सेवा की थी।

श्री टंडन बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट, विधायक और सरकारी नेताओं के अनचाहे गठजोड़ ने महापालिकाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को खतम कर दिया है। नौकरशाही के बढ़ते असर के सामने आम जनता तो बेबस है ही, सरकार के मंत्री भी असहाय से लगते हैं।

श्री रिजवी की मांग है कि सरकार एक ऐसा आयोग बनाये, जो महापालिका में दस साल तक जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्यों, भ्रष्टाचारों और उनकी मनमानी कार्यवाहियों की जांच करे और उनकी तुलना प्रशासकों के सत्रह साल के क्रियाकलापों से करे। ईमानदारी से आयोग की रिपोर्ट जनता की अदालत में रखी जाये और मतदाताओं को खुद फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाये।

तब और अब की नगर महापालिका के कामों का अन्तर बताते हुए वह कहते हैं, "उस वक्त के खर्च और अब के खर्चों में बड़ा फर्क है। तब खर्चों पर सभासदों की निगरानी रहती थी और हम बजट के खर्चों से होने वाले कामों पर नजर गड़ाये रहते थे। अब किसी को चिंता नहीं है। नौकरशाही आजाद है। मनमाने ढंग से खर्चे किये जाते हैं और कहीं कोई अंकुश नहीं। तब हमें जनता के सामने जवाब देना पड़ता था, अब वे खुद हाकिम हैं।"

बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में लालजी टंडन बताते हैं—"पिछले पांच सालों में प्रदेश की राजधानी में न तो कोई नयी सीवर लाइन डाली गयी है और न ही नयी पाइप लाइन। १९७४ में विश्व बैंक से बीस करोड़ रुपए मिले थे। उसी समय जल निकास योजना बनायी गयी, लेकिन एक तिहाई काम भी पूरा नहीं हुआ और सारा रुपया खर्च हो गया। इस योजना के तहत सात क्षेत्रीय पम्पिंग स्टेशन, ४० ट्यूबवेल और दो नये वाटर वर्क्स बनाये जाने थे, लेकिन इस समय सिर्फ चार क्षेत्रीय पम्पिंग स्टेशन, ११ ट्यूबवेल ही काम कर रहे हैं। दो नये 'वाटर वर्क्स' की योजना खटायी में पड़ गयी है। अगर जनप्रतिनिधि होते, तो जनता के सामने यह बात खुलासा हो जाती कि २० करोड़ रुपए कहां खर्च हो गये, किसकी जेब में गये? अब भला कौन पूछेगा, उनसे इस बारे में?" फिजूल खर्ची के बारे में रिजवी भी कहते हैं, "भवन कर-निर्धारण के मामले को लीजिए। अधिनियम की धारा ५०६ से ५१२ तक में कर-निर्धारण का मापदण्ड निर्धारित है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। भवनों पर ८० और ९० प्रतिशत तक कर बढ़ा दिये गये, जबकि अधिनियम के तहत २५ प्रतिशत से ज्यादा कर नहीं लगाये जा सकते हैं। इसी तरह जल-कर के निर्धारण में धांधली हो रही है। मजे की बात यह है कि दैनिक कर्मचारियों से कर-निर्धारण कराने में पूरे प्रदेश में ५५ लाख रुपए खर्च हुए। इस अंधाधुंध तरीके से हुए कर-निर्धारण को लेकर जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, तब जाकर वीर बहादुर सिंह ने उसे स्थगित किया। अब सवाल उठता है कि इस गलत कर-निर्धारण में जो ५५ लाख रुपए खर्च हुए, उसका जवाबदेह कौन होगा?"

डाक्टर सिद्धू का कहना है, "तब नगर महापालिका की बैठक में किस मद पर कितना खर्च किया जाये, यह तय होता था। अब तो खर्च होने वाली राशि का पता नहीं चलता। तब बैठक में सब खुलासा हो जाता था। जब तक चुने प्रतिनिधि महापालिकाओं में नहीं होंगे, तब तक जनता को कामों और खर्चों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकती।"

—लखनऊ ब्यूरो

मदन मोहन सिंह सिद्धू

शाहिद हुसैन

लालजी टंडन

में उसे विधायक की चिरौरी करनी पड़ती है। चाहे मोहल्ले की गंदगी की समस्या हो या अंधाधुंध तरीके से लगाये गये भवन कर का मामला हो, इनके समाधान के लिए जनता के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। वह या तो विधायक या सांसद के सामने गिड़गिड़ाये या फिर नौकरशाहों की मुट्ठी गर्म करके काम निकाले। भला जब सभासद हो जायेंगे, तो विधायक और सांसद को कौन पूछेगा? स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व विहीन रखने के पीछे बडे नेताओं का अपना स्वार्थ है।''

लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि अगर सभासद चुन लिये जायें, तो जनता नौकरशाहों से मुक्ति पा जायेगी। इस बारे में कानपुर नगर महापालिका में पिछले १४ वर्षों से एक उच्च पद पर कुंडली मारे बैठे अधिकारी का कहना है, ''हमने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। सभासद एक नही दस चुन लिये जायें, हम तो उसी तरह काम करेंगे जैसे वर्षों से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम परमानेंट (स्थायी) हैं और सभासद 'टेम्प्रेरी' (अस्थायी) होंगे। हम पर कोई शासन न कर सके, हमने इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। जैसे ही चुनी हुई महापालिकाएं खत्म हुई, हमारी बिरादरी (नौकरशाहों) वालों ने महापालिका को तीन टुकड़ों में बटवा दियां। विकास प्राधिकरण और जल संस्थान को टुकड़ों के रूप में महापालिका से अलग कर दिया। अब अगर सभासद चुनकर आयेंगे भी, तो केवल महापालिका में झाड़ू-पोंछा ही देखेंगे। हलवा-पूड़ी तो हम और हमारे अफसर खायेंगे।''

इस अफसर की बात में काफी दम है। सत्रह वर्ष पूर्व महापालिका में सभासद या नगर प्रमुख शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक की देखभाल करता था, लेकिन इन १७ वर्षों में स्थिति काफी बदल चुकी है। आठों महापालिकाओं से विकास कार्य और जल आपूर्ति का काम लेकर विभागों को सौंप दिया गया है। यही नहीं, अलीगढ़, गाजियाबाद और मुरादाबाद में महापालिकाएं न होने के बावजूद वहां विकास प्राधिकरण बना दिये गये हैं। अब अगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव हो भी जाते हैं, तो विकास के नाम पर हलवा पूड़ी, नौकरशाह खायेंगे और झाड़ू-पोंछे के साथ जनता का कोपभाजन सभासद बनेंगे।

भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार: विकास प्राधिकरणों में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक अनुमान के अनुसार मकान के नक्शे पास कराने से लेकर आवासीय भवनों के निर्माण और आवंटन में पांच बड़े नगरों में स्थित विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी प्रतिदिन लगभग नौ लाख रुपये 'ऊपरी कमाई' करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विकास प्राधिकरण के जिस उपाध्यक्ष के विरुद्ध 'स्ट्रिक्चर' (भर्त्सना) पास करते हुए सरकार को उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा था, वह अधिकारी आज भी मूंछों पर ताव देकर घूम रहा है क्योंकि वह अधिकारी आई०ए०एस० तो है ही, परंतु राजनीति में सक्रिय ब्राह्मण लाबी का भी उस पर वरदहस्त है।

ठीक यही स्थिति महापालिका से अलग हुए जल संस्थानों की है। वहां जिस तेजी से पानी सूख रहा है, उससे दूनी तेजी से भ्रष्टाचार की बाढ़ आ रही है। वाराणसी में जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जा रहे जल के नमूनों की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीनें के उस पानी में ११ से लेकर २१ प्रतिशत. तक मल-मूत्र होता है। कानपुर में दूषित जल की आपूर्ति से पेट के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कुछ वर्ष पूर्व तक शहरी सफाई और प्रकाश-व्यवस्था के साथ-साथ नगर महापालिकाओं पर सीवर सफाई की भी जिम्मेदारी थी लेकिन अब यह भार भारी बजट के साथ जल-संस्थानों को सौंप दिया गया है, ताकि वे सीवर लाइनों की गंदगी पीने के पानी की लाइन में आसानी से मिला सकें। आखिर मिलावट का जमाना जो ठहरा!

बहरहाल उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानीय निकाय के चुनाव इस वर्ष के अंत तक करा देने का निर्देश देकर वीर बहादुर सिंह को असमंजस की स्थिति में ला दिया है। अब अगर चुनाव नहीं होते तो अदालत की मानहानि के साथ जग हंसाई भी होगी और अगर वीर बहादुर चुनाव कराते हैं, तो चुनाव से पूर्व ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के नेताओं को गुटबंदी झेलनी पड़ेगी। फिर, अगर चुनाव में कहीं पलड़ा विपक्ष का भारी हो गया, तो मुख्यमंत्री की पद-प्रतिष्ठा पर यकीनन आंच आयेगी।

मत-मतांतर: इस बारे में इंका की नगर विकास सेल के प्रान्तीय संयोजक शाहिद हुसैन रिजवी का कहना है, ''तीस प्रतिशत स्थान तो हम जैसे-तैसे जीत ही लेंगे। ले जाने दीजिए विपक्ष को तमाम स्थानीय निकाय। अभी आम चुनाव में दो-तीन साल का समय बाकी है। विपक्ष की गलतियों को हम आम चुनाव के समय उजागर कर फायदा उठा सकते हैं। फिर अगले चुनाव में पार्टी की जीत के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव कराना हमारे लिए वरदान साबित होगा। चुनाव न होने की दशा

प्रशासक के भरोसे लखनऊ जल संस्थान

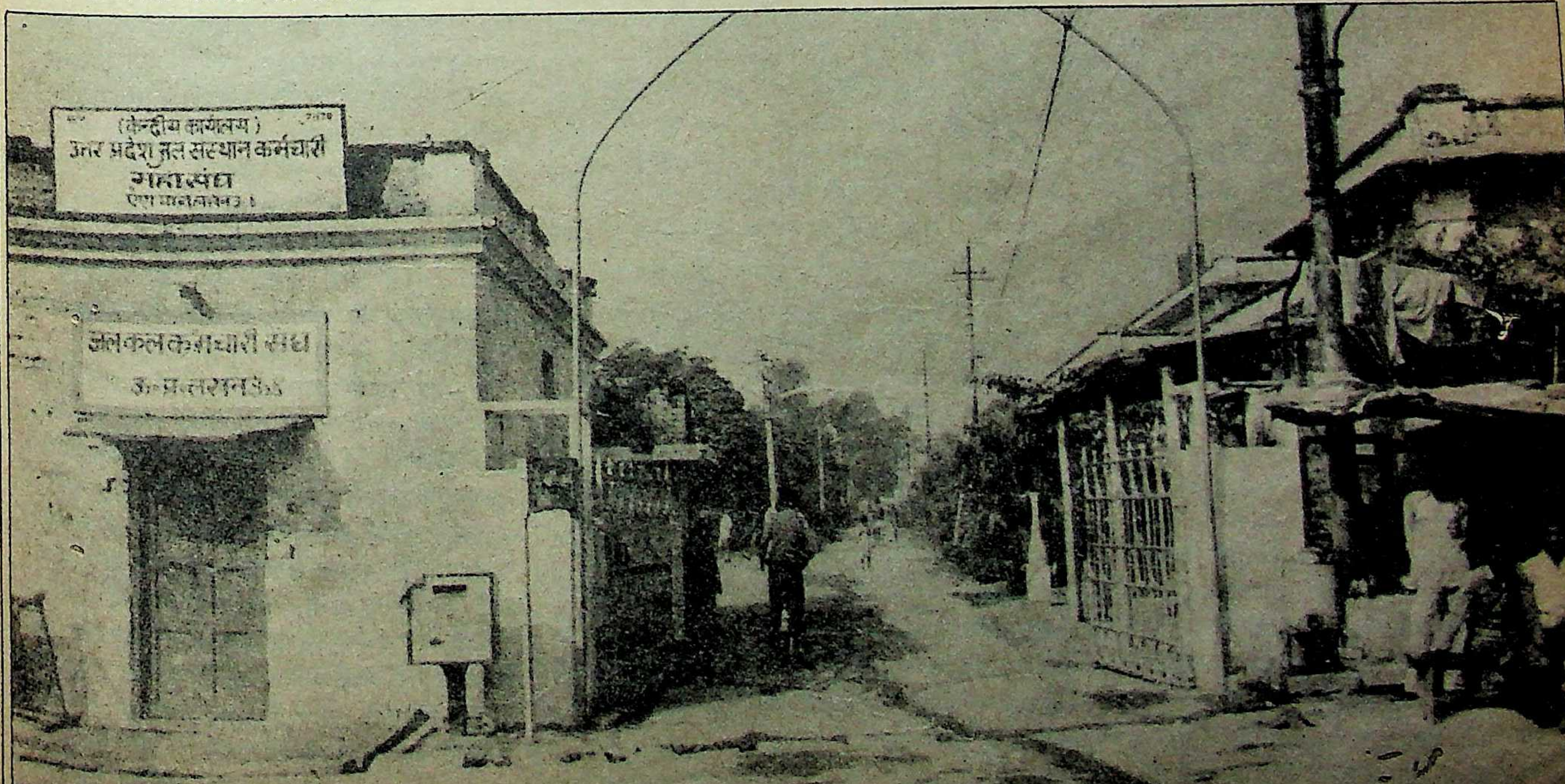

में आम चुनाव के समय अफसरों के कुकृत्यों का जवाब देते-देते हमारा पसीना छूट जायेगा। मैंने अपने इस विचार से संगठन के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया है। अब निर्णय लेना उनका काम है।" लेकिन इसके जवाब में वीर बहादुर सिंह कहते हैं, "इस समय प्रदेश में सूखे की विकट समस्या है। पहले हम उससे निपट लें, तब चुनाव के बारे में सोचेंगे। फिर चुनाव के बिना जनता का कौन सा काम रुका हुआ है। नगर विकास विभाग मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं। जैसे ही मुझे शिकायत मिली कि भवन कर निर्धारण में गड़बड़ी हुई है, मैंने उसे रद्द कर दिया। सभी जगह यह आदेश एक बार में ही लागू हो गया। अगर चुनी हुई महापालिकाएं होतीं, तो क्या एक साथ ऐसा आदेश सब जगह लागू हो सकता था।"

दूसरी ओर चुनाव निदेशालय स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए काफी हद तक तैयार है। महापालिकाओं के वार्डों के परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। अब मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम चालू है। चुनाव निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, "हमारी तैयारी जारी है। हमने सरकार को भी सूचित कर दिया है। अदालत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए चुनाव कराने या न कराने का फैसला अब सरकार को ही करना है।

स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की कानूनी लड़ाई का दिलचस्प पहलू यह भी है कि १४ मई के फैसले से पूर्व सरकार ने अदालत में न्यायमूर्तियों के कहने के बावजूद कोई प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। सरकार की तरफ से फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक प्रार्थना-पत्र अवश्य दाखिल किया गया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने की इजाजत भी सरकार को नहीं मिली है।

याचिका दायर करने वाले वकील श्री द्विवेदी का विचार है, "सरकार उच्चतम न्यायालय जा सकती है, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 'कैवियट' (आपत्ति सूचना) लगा दी है। चुनाव न होने की दशा में मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए भी सारी तैयारी कर चुका हूं। देखना है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर लगी जंग को मिटाने में न्यायपालिका की जीत होती है या फिर इस सीढ़ी को तोड़ने में सरकार सफल होती है।"

वैसे भी विधानमंडल के दोनों सदनों में वीर बहादुर की सरकार यह वादा कर चुकी है कि वह ३१ दिसम्बर, १९८७ तक स्थानीय निकायों के चुनाव करा देगी, लेकिन, राजनीतिक हलकों में अदालती फैसले और सदन में सरकार के आश्वासनों के आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि सरकार कोई 'सरप्राइज' देगी। चुनाव कराने की अचानक घोषणा करने पर विभिन्न पार्टियों का रुख क्या होगा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं।

—अशोक रजनीकर

किस्सा मेयर की मजबूरी का

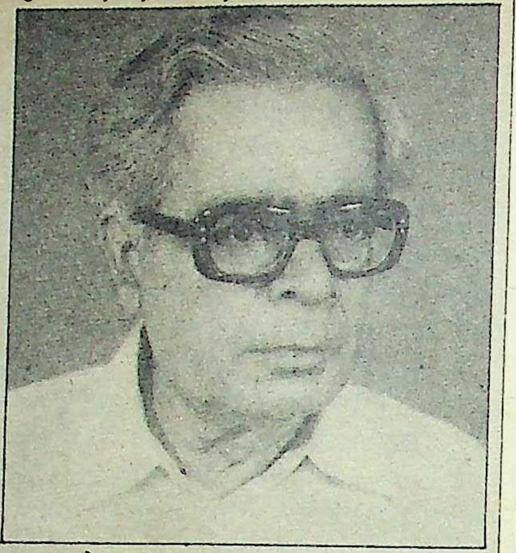

डा० पुरुषोत्तम दास कपूर

डाक्टर पी०डी० कपूर लखनऊ की जानी-मानी हस्ती हैं। नगर महापालिका के वह दो बार मेयर रह चुके हैं। उस समय की नगर महापालिका और आज की नगर महापालिका का उनका अपना तजुर्बा है, कुछ मीठा और कुछ खट्टा।

डाक्टर कपूर अपने अनुभव सुनाते हैं, "जब मैं नया-नया मेयर बना था, तब मेरे एक घनिष्ठ मित्र एक नक्शा लेकर मेरे पास आये और उसे पास करा देने का आग्रह करने लगे। मैंने सम्बन्धित अधिकारी को बुलाया तथा उसे एक सप्ताह में नक्शा पास करवाने की हिदायत दी। मित्र को एक सप्ताह बाद आने को कहा। एक सप्ताह के बाद उसके आने पर मैंने सम्बन्धित अधिकारी को तलब किया। अधिकारी फाइल लेकर आया। उसमें नोट लगाया था कि नक्शे में दिखायी गयी जमीन का एक छोटा भाग नजूल का है। अधिकारी ने कहा, "सर, आप आदेश दें, तो इसे पास कर दूं।" भला मैं कैसे नियम के खिलाफ काम करवा सकता था। अपने दोस्त से मजबूरी जाहिर की। तीन महीने बाद वही दोस्त फिर आये। इस बार उसने वही पुराना नक्शा सामने रखते हुए कहा, "यह न पूछना कि यह कैसे पास हो गया है?"

"जब मैं मेयर नहीं रहा, तब उस मित्र से नक्शा पास होने और नजूल की जमीन गायब होने के बारे में जानना चाहा, तो उसने बताया कि क्लर्क को सौ रुपए दिये थे। बस नजूल की जमीन भी गायब हो गयी तथा नक्शा भी पास हो गया। सही बात है मेयर की हैसियत नजूल की जमीन गायब कराने की नहीं, जबकि क्लर्क में इससे बड़ी ताकत है।"

इसी तरह का एक दूसरा मामला डाक्टर कपूर इस तरह बताते हैं, "अब दूसरा किस्सा भी सुन लो, मेरे अपने नक्शे के बारे में। बात प्रशासक राजीव रत्न शाह के वक्त की है। मैंने अपने ड्राइवर को घर बनवाने का एक नक्शा दिया और कहा कि इसे जमा कर आओ। ड्राइवर ने वापस आकर बताया कि नक्शा पास होने के लिए पांच विभागों में जाता है। हर विभाग के लिए ५० रुपए के हिसाब से २५० रुपए दस्तूरी मांगी जा रही है। जब हमारे ड्राइवर ने वहां कहा कि रुपए नहीं हैं और हमारे साहब तो आपके मेयर रह चुके हैं, तो संबंधित क्लर्क ने कहा, 'रख जाओ, पास हो जायेगा।' मैं दो साल तक नक्शा पास होने का इंतजार करता रहा। हारकर प्रशासक के पास पहुंचा और अपनी दास्तान सुनायी। प्रशासक ने कहा, 'डाक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। एक सप्ताह के बाद मुझसे मिल लीजिए।' कोई दस दिन बाद पहुंचा, तो पता चला कि संबंधित फाइल मिल नहीं रही है। फिर एक सप्ताह की मोहलत प्रशासक महोदय ने मांगी। दुबारा पहुंचा तो फाइल प्रशासक के पास ही थी और नक्शे में १५ कमियां दिखायी गयी थीं। प्रशासक ने कहा कि इन्हें दूर करा लें, तो आपका नक्शा पास हो जायेगा। राजीव रत्न शाह बेबस थे और मैं सिर पीटकर रह गया। अच्छा होता २५० रुपए भिजवा देता। अब तो फिर से नक्शा बनवाने में ही ३५० रुपए लग जायेंगे। दो साल का वक्त भी मुफ्त गंवाया। मजबूरन नया नक्शा बनवाना पड़ा जो प्रशासक की दिलचस्पी लेने के बावजूद ६ महीने से पहले पास नहीं हो सका।

इन दो किस्सों को सुनाने के बाद साहब ने कहा, "जनता के चुने प्रतिनिधियों के जमाने में नक्शा पास कराने की दस्तूरी सौ रुपए थी और अब प्रशासक के जमाने में २५० रुपए से लेकर ढाई हजार तक है। दोनों जमाने के काम का ढर्रा बता दिया है। अब जो चाहो निष्कर्ष निकाल लो।"

—लखनऊ ब्यूरो

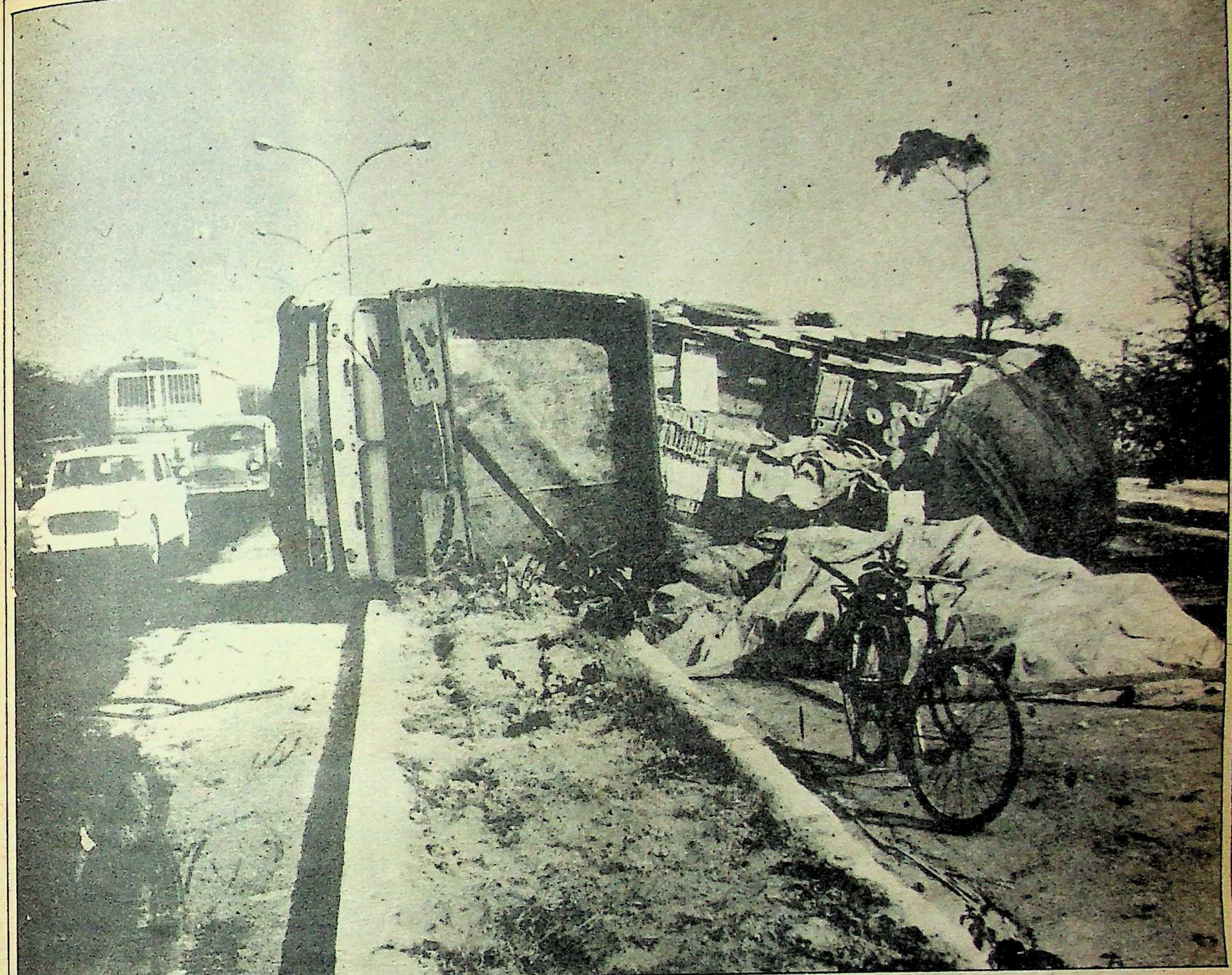

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

कदम-कदम पर मौत

जिन्दगी की भागती दौड़ में
परिवहन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है,
लेकिन इस आपा-धापी में
हम अपने उद्देश्य पर पहुंचने से पहले ही मौत को गले लगा बैठते हैं।
इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं—
हम, हमारी लापरवाही
या ट्रैफिक कानून-व्यवस्था?

आई०टी०आई० के प्रोफेसर और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सलाहकार डा० दिनेश मोहन के अनुसार, "बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं अब एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर रही हैं। पिछले साल केवल सड़क दुर्घटनाओं में ही ४०,००० लोगों की मृत्यु हो गयी थी, जबकि १९८० में यह संख्या २४,६०० थी। यह संख्या हर साल १२३ 'कनिष्क' विमान दुर्घटनाओं के बराबर या हर तीन दिन में एक कनिष्क दुर्घटना होने के बराबर है।"

एक तिहाई से ज्यादा दुर्घटनाएं केवल महानगरों में होती हैं। राजधानी दिल्ली में ही हर साल सड़क दुर्घटनाओं से मरनेवाले लोगों की संख्या हजार पार कर जाती है। इसके अलावा सैकड़ों लोग गंभीर चोटों के शिकार हो जाते हैं। सचाई यह है कि सड़क दुर्घटनाओं की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर है। आग या रेल दुर्घटनाओं से [illegible] बड़ा खतरा दिल्लीवासियों के सिर पर मंडराता रहता है।

वर्ष १९८६ में दिल्ली की सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें

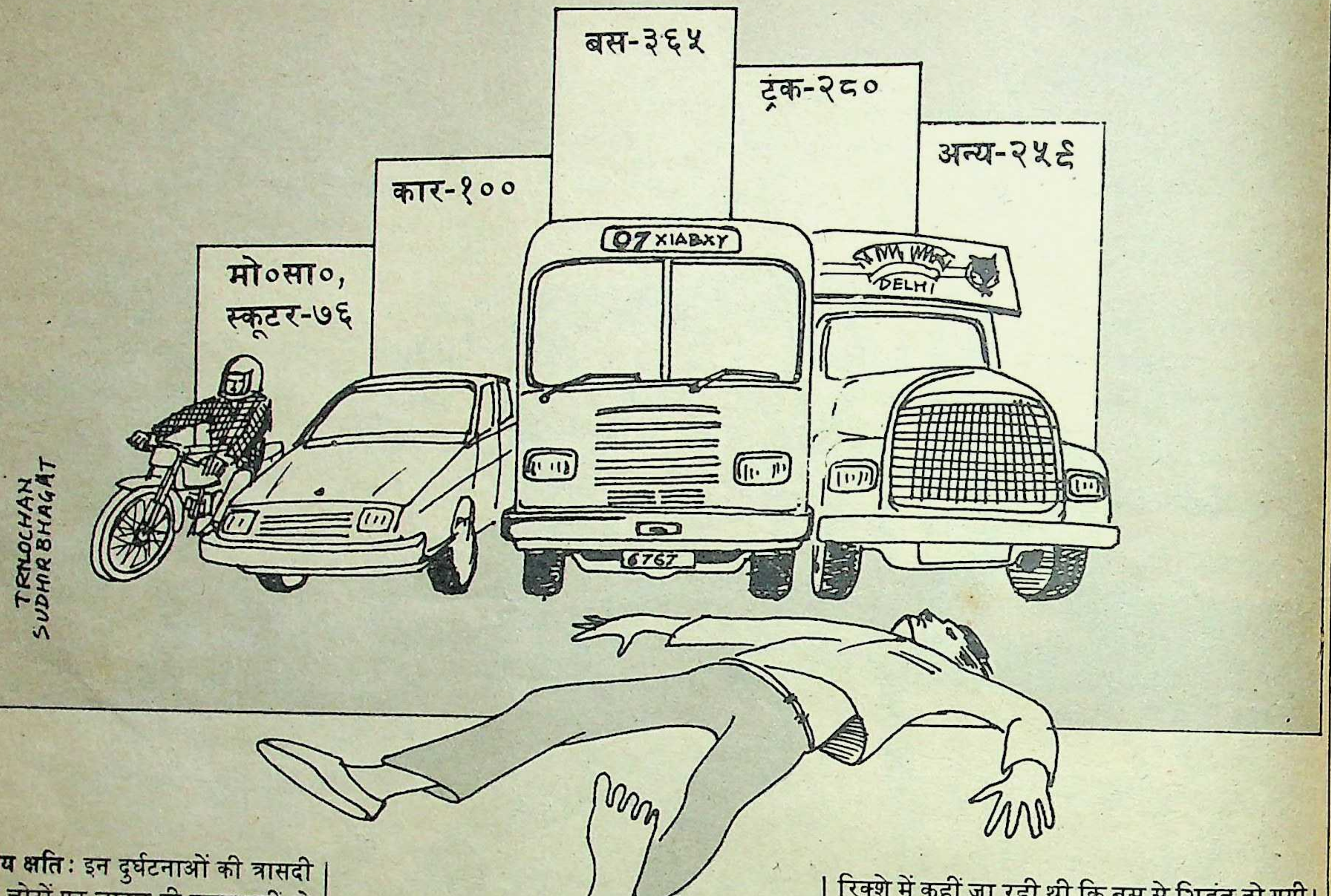

अपूरणीय क्षति : इन दुर्घटनाओं की त्रासदी मृत्यु या गंभीर चोटों पर जाकर ही खतम नहीं हो जाती। दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति का पूरा परिवार उजड़ जाता है। श्रीमती कमलेश सिंह के पति की चार साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। इस आघात से उनका परिवार आज तक उबर नहीं पाया है। श्रीमती सिंह कहती हैं, "जैसे वह कल की ही बात हो। वह सर्दी की एक सुबह थी। मेरे पति सुबह छह बजे चले गये थे। वह गुड़गांव में काम करते थे। लगभग दो घंटे बाद घंटी बजी। मैं उस समय आफिस जाने वाली थी। एक गमगीन व्यक्ति ने मेरे पति का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हुए कहा कि आपके पति बुरी तरह से घायल हो गये हैं और सफदरजंग अस्पताल में जीवन-मृत्यु के बीच झूल रहे हैं।' मैं तुरंत अस्पताल पहुंची, मगर तब तक वह इस संसार से विदा हो चुके थे। इस हादसे के कारण श्रीमती सिंह ४२ वर्ष की उम्र में ५५ वर्ष की नजर आने लगी हैं। उन्होंने अपना तीन बेडरूम वाला मकान बेच दिया है और विस्थापितों की कालोनी में एक-दो कमरों के फ्लैट में रहने लगी हैं। अपने तीनों बच्चों को उन्होंने पब्लिक स्कूल से निकाल लिया है और रहन-सहन में भी काफी सादापन आ गया है। अब पूरा परिवार श्रीमती सिंह की १२०० रुपए प्रतिमाह की तनख्वाह पर निर्भर है।

सुशील[illegible] की स्थिति श्रीमती सिंह से ज्यादा दुखद है। वह अपने पिता के साथ एक आटो रिक्शे में कहीं जा रही थी कि बस से भिड़ंत हो गयी। आटो चालक और सुशीला के पिता की मृत्यु तो घटनास्थल पर ही हो गयी। सुशीला के दोनों पैर सिटी बस के नीचे आ गये, फलस्वरूप काटने पड़े। यह तीन महीने पहले की घटना है। सुशीला की नौकरी छूट गयी है और अब दोबारा चल नहीं सकती। सुशीला की मां कहती हैं, "हम लोग इस साल उसकी शादी करने की सोच रहे थे, मगर अब उससे कौन शादी करेगा ?"

अपर्याप्त ट्रैफिक पुलिस : आम तौर पर इन दुर्घटनाओं के लिए ट्रैफिक पुलिस और नागरिक अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। सड़क नियमों की अनदेखी भी दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है। दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त एस०बी० देओल कहते हैं, "मैं स्वीकार करता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तर्क में बहुत कम सचाई है कि ट्रैफिक पुलिस अव्यवस्था उत्पन्न करती है। शुरू से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कम लोग हैं।" यह सभी महानगरों के लिए सचाई है। १९८० के बाद से ट्रैफिक पुलिस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी, जबकि ट्रैफिक असाधारण रूप से बढ़ा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में वाहनों की संख्या १,१८,९९,५६ हो गयी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां और भी बढ़ी हैं। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या आयोजन दिल्ली और बंबई में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों में पुलिस की बहुत जरूरत पड़ती है।

एक तिहाई से ज्यादा दुर्घटनाएं केवल महानगरों में होती हैं। राजधानी दिल्ली में ही हर साल सड़क दुर्घटनाओं से मरनेवाले लोगों की संख्या हजार पार कर जाती है। इसके अलावा सैकड़ों लोग गंभीर चोटों के शिकार हो जाते हैं। सचाई यह है कि सड़क दुर्घटनाओं की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर है। आग या रेल दुर्घटनाओं से भी बड़ा खतरा दिल्लीवासियों के सिर पर मंड़राता रहता है।

घटिया ट्रैफिक इंजीनियरिंग : घटिया ट्रैफिक इंजीनियरिंग और दूरदृष्टि का अभाव दुर्घटनाओं का एक और बड़ा कारण है। सड़कों के निर्माण संबंधी योजनाओं को बनाते समय 'संकेतों' आदि के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। योजना के कागजों में पार्किंग क्षेत्र दर्शाया जाता है, मगर जब निर्माण-कार्य पूरा होता है, तो सब गायब। लिहाजा लोग सड़क के किनारे पैदल मार्ग पर या इमारतों के सामने अपने वाहन खड़े करते हैं और पैदल यात्रियों को मजबूरन खतरा उठाकर सड़क पर चलना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती। नागरिक अधिकारी ही इस संदर्भ में नियम-कानून बनाते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पूछता है, "क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाला हर दूसरा पैदल यात्री होता है ? और उन लोगों का क्या किया जा सकता है जो मारुति चलाते हुए टी०वी० में रामायण और चित्रहार देखते हैं ? ऐसे चालकों से कैसे निपटा जाये जो पुलिस की डपट पर लाइन में आ जाते हैं और उनके हटते ही अव्यवस्था फैला देते हैं।" यह संभव नहीं है कि हर सड़क के हर हिस्से का ध्यान रखा जाये। दिल्ली के चालक तो कानून तोड़ने में माहिर हैं। दिल्ली पुलिस हर दिन लगभग २५,००० लोगों का चालान करके १.२५ लाख रुपए जुर्माना वसूलती है। हर साल दिल्ली पुलिस २.५ करोड़ रुपए इस जरिये से सरकार को सौंपती है। इस सबसे कुछ नियमों, जैसे—हेलमेट लगाने आदि का पालन होने लगा है।

सड़क दुर्घटनाएं अब राष्ट्रीय समस्या : डा० दिनेश मोहन

दूषित लाइसेंस प्रणाली : सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लाइसेंस प्रणाली में सुधार भी हो सकता है। ज्यादातर स्थानों पर एक वाहन निरीक्षक (वेहिकिल इंसपेक्टर) हर दिन ५०० नये चालकों को टेस्ट करके प्रमाण-पत्र देता है। निश्चित रूप से वह सब हड़बड़ी में होता है। बिना कोई टेस्ट दिये लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। २०० रुपए खर्च करके कोई भी लाइसेंस बनवा सकता है।

राजधानी में दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण चौड़ी खुली सड़कों का होना भी है। बंगलौर, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में ट्रैफिक बहुत धीमा होता है, इसलिए दुर्घटनाएं भी आधी होती हैं। डा० मोहन कहते हैं, "औसत गति बहुत ज्यादा होने की वजह से दिल्ली में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं।" दिल्ली की चौड़ी सड़कें लोगों को तेज वाहन चलाने के लिए प्रेरित करती हैं। यहां तक कि स्वयं तेज गति से वाहन चलाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते।

सुरक्षा के उपाय : डा० मोहन कुछ सुरक्षा उपायों की चर्चा करते हुए कहते हैं, "हेलमेट पहनना, साइकिलों पर चमकीले पीले, नारंगी या सफेद रंग करवाना, सड़क के किनारे खाली रखना ताकि ट्रैफिक लाइट साफ दिखायी दें, मारुति जैसी हलकी कारों में प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री रखना तथा सड़क निर्माण की कोई भी नयी योजना पारित करते समय ट्रैफिक सुरक्षा को ध्यान में रखना

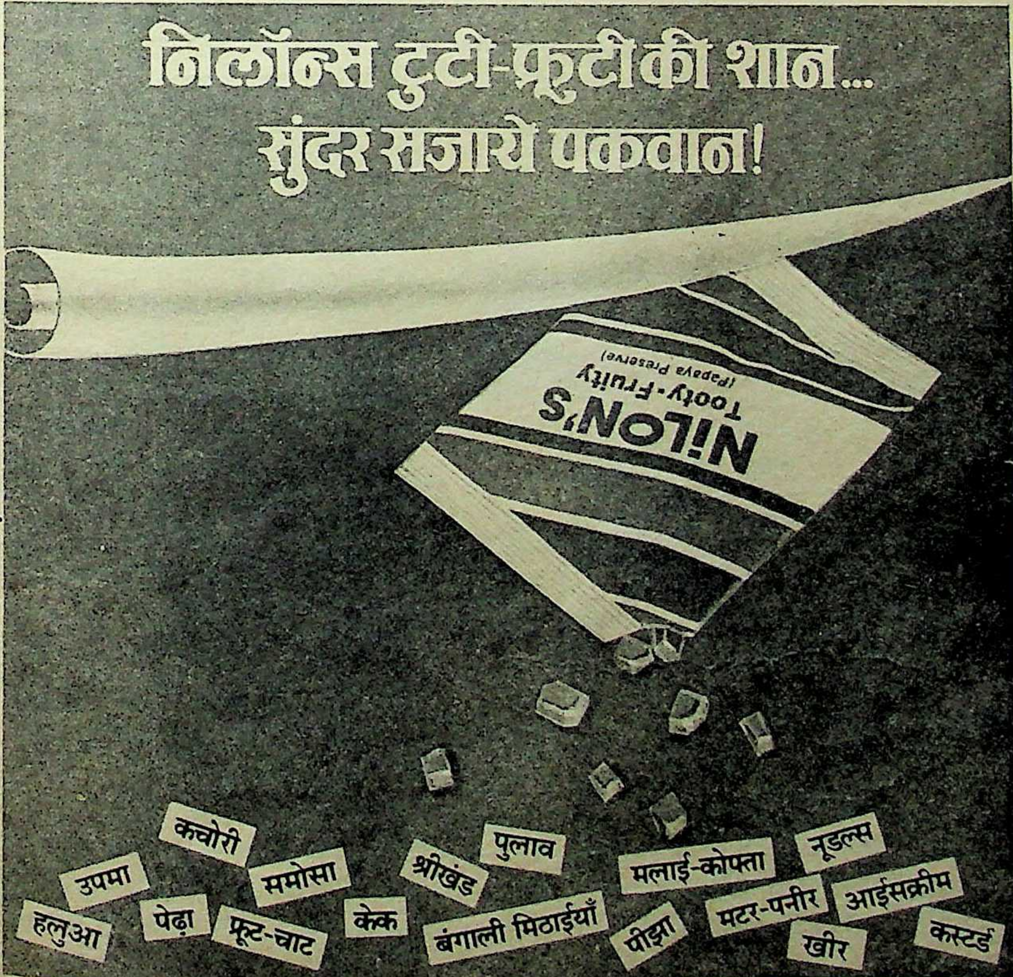

कुशल गृहिणी की खासीयत तो है ही स्वादिष्ट पकवान... लेकिन इनको आप निलॉन्स टुटी फ्रूटी से सजाएँ तो चार-चाँद लग जाएँ।
निलॉन्स टुटी फ्रूटी की विशेषताएँ...
- सबसे ज्यादा चमक
- भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाली
- अत्याधुनिक ढंग से बनी हुअी
- अब घरेलू इस्तेमालके लिए १०० ग्रॅम के छोटे पॅक एवं चार आकर्षक रंगोमें उपलब्ध।
निलॉन्स टुटी-फ्रूटी केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित 1021 R चिन्ह देखकर ही खरीदिये।
FPO

NILON'S
निलॉन्स
फूडस् प्राईव्हेट लिमिटेड
निलॉन्स हाऊस, जलगाँव
(महाराष्ट्र) ४२५ ५०१.
भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाले निलॉन्स अचार के निर्माता एन-ज़ॉय सॉफ्ट ड्रींक कॉन्सेंट्रेटके [illegible]ादक।

AD HOUSE 1003 HIN

आदि कुछ महत्वपूर्ण उपाय करके दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। सबसे ज्यादा मौतें मोटर साइकिल और स्कूटर चालकों की होती हैं। इनकी संख्या बस यात्रियों और कार धारकों के मुकाबले पांच गुनी और तिपहियों के मुकाबले दोगुनी होती है। वास्तव में हर १००० दुपहियों से पांच लोग मरते हैं। सरकार को १५० सीसी से ज्यादा क्षमता वाले दुपहियों के निर्माण को हतोत्साहित करना चाहिए और सन २००० तक इनको पारिवारिक प्रयोग से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर यह होगा कि वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाये।

दुर्घटना के मुख्य कारण: दुपहियों के बाद दुर्घटना के सबसे बड़े कारक बस और ट्रक हैं। पिछले साल होने वाली आधी से ज्यादा दुर्घटनाओं में बस और ट्रकों का हाथ था। डा० मोहन बताते हैं, "दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) की बसों से मरे व्यक्तियों की संख्या (५२७२) कलकत्ता के सभी वाहन चालकों के हाथों मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से भी ज्यादा है।" बेफिक्र चालन और बसों की खस्ता हालत इसके लिए दोषी है। जब प्रबंध चालकों से इस असावधानी का कारण पूछा जाता है, तो जवाब मिलता है कि उन्हें दी जाने वाली बसों की तगड़ी ओवरहालिंग की जरूरत है।

डी०टी०सी० के प्रबंधक पुरेन्दु दत्ता के अनुसार लंबी दूरी तक सबसे ज्यादा यात्रियों को लाने-ले जाने के बावजूद डी०टी०सी० की सेवा बंबई और मद्रास (पल्लवन) से बेहतर है। हर एक लाख किलोमीटर में 'पल्लवन' की दुर्घटना दर ३.३० है जबकि डी०टी०सी० की १.६७।

बहरहाल, अन्य शहरों के मुकाबले डी०टी०सी० पर ज्यादा बोझ है। डी०टी०सी० हर दिन औसतन ४६.५ लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती है और इसके लिए उसे १०.१ लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। डी०टी०सी० की दैनिक आय ३५ लाख रुपए है। डी०टी०सी० की टक्कर ज्यादातर दुपहिया वाहनों से होती है और आम तौर पर दुपहिया चालक की मृत्यु हो जाती है।

दत्ता इस बात से सहमत हैं कि जल्दी ही एक वैकल्पिक परिवहन तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा चल रही है। पूर्व से पश्चिम दिल्ली तक चुंबकीय ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव है।

परिवहन मंत्रालय ने 'खराब चालक, खराब वाहन और खराब सड़कें' कहकर दुर्घटनाओं के मामले से किनारा कर लिया है। लेकिन बढ़ती दुर्घटनाओं ने सरकार को सावधान किया है। हाल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जो नये जन परिवहन तंत्र के बारे में अध्ययन करेगी। लेकिन नये सड़क नियम बनाने का काम भी आसान नहीं है। वाहन निर्माताओं का ध्यान भी इस ओर खींचना होगा कि वे सीट बेल्ट इत्यादि जोड़कर वाहनों को और सुरक्षित बनायें। सरकार लाइसेंस प्रणाली को भी कड़ी करने का विचार कर रही है, लेकिन जब तक इन कार्यवाहियों पर अमल होगा और हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके होंगे।

—शशि सनी

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

क्या मारुति से बढ़ी हैं दुर्घटनाएं?

तेज किंतु नाजुक कार मारुति और तेज गति के दुपहिया वाहनों—जैसे, यामहा आदि के आने से नौजवान राजधानी की सड़कों पर तेज गाड़ियां चलाने को प्रोत्साहित हुए हैं। डा० दिनेश मोहन (ट्रैफिक इंजीनियरिंग सलाहकार) के अनुसार दुर्घटनाओं और गति के बीच सीधा संबंध है। दिल्ली में वाहनों की औसत गति सबसे ज्यादा है, इसलिए दुर्घटनाएं भी वहां सबसे ज्यादा होती हैं।

ज्यादातर दिल्लीवासी महसूस करते हैं कि बढ़ती दुर्घटनाओं का कारण मारुति कारों की बढ़ती संख्या है। लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राज भार्गव इस तर्क से सहमत नहीं हैं। वह कहते हैं, "मारुति के आने के पहले भी दिल्ली में दुर्घटना दर सबसे ज्यादा रही है। फिर हमारी कारों पर ही पूरा दोष क्यों मढ़ा जा रहा है?" लेकिन ट्रैफिक शोधकों के अनुसार विश्व में हर जगह छोटी कारें ही ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और घायलों या मरने वालों की संख्या भी छोटी कारों में बैठे व्यक्तियों की ज्यादा है। कुल एक करोड़ वाहनों में से १५ लाख कारें हैं और इनमें से दस प्रतिशत से ज्यादा मारुति हैं।

प[illegible] प्रतिशत कारें, बस और ट्रक से टक[illegible]र्घटनाग्रस्त होती हैं। ज्यादातर चालक इस बात से सहमत हैं कि मारुति की नाजुक बाडी असुरक्षित है, जबकि भार्गव कहते हैं, "यह बिलकुल गलत धारणा है। सचाई यह है कि मारुति को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि दुर्घटना होने पर चालक को कम-से-कम चोट पहुंचे, चाहे कार को कितना ही नुकसान हो। मारुति में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे और पीछे के पैनल इसी आधार पर डिजाइन किये गये हैं कि दुर्घटना होने पर चोट उन्हीं को झेलना पड़े और सवारियां सुरक्षित रहें। दुर्भाग्यवश भारतीय चालक सभी सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाते हैं और फिर मारुति को नाजुक बताते हैं। यद्यपि हमने कोई अध्ययन नहीं कराया है, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, कि यदि कोई अध्ययन हो, तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि मारुति की उपेक्षा अन्य कारों से ज्यादा लोग मरते हैं।"

जापान में मारुति से कम शक्तिशाली ५५० सीसी की सुजुकी बहुत लोकप्रिय है। तो क्या मारुति में भी ५५० सीसी का इंजन लगाना ठीक नहीं होगा? भार्गव इससे असहमति जताते हैं, "५५० सीसी का इंजन भारतीय परिस्थितियों में ठीक नहीं होगा, क्योंकि जापानी कारों से ज्यादा भार ढोने की क्षमता भी हमें चाहिए। भारत में हर कार में बहुत सवारी और ढेर-सा लगेज लादा जाता है, जबकि जापान में छोटी कार प्रायः एक व्यक्ति के उपयोग में आती है। एक भारतीय का औसत भार भी किसी जापानी से ज्यादा होता है। ५५० सीसी का इंजन लगाने का एक कारण और भी है। कार को वातानुकूलित रखने के लिए जापान के मुकाबले शक्तिशाली इंजन की जरूरत पड़ती है। भारत में तापमान ४५° सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि जापान में ३२° सेंटीग्रेड तक भी मुश्किल से पहुंचता है।"

बहरहाल, भार्गव इस बात पर सहमत हैं कि सुरक्षा ब्रेल्ट और शीशे जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये उपाय जापान में १९८६ से इस्तेमाल किये जाने लगे हैं। लेकिन इससे कारों के दाम बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर एक डीलक्स कार में सुरक्षा बेल्ट लगाने से ८०० रुपए कीमत बढ़ जायेगी। ज्यादातर भारतीय सुरक्षा के लिए यह कीमत देने को तैयार नहीं होंगे। अतः हमें क्या करना चाहिए कि खरीदारों में सुरक्षा बेल्ट लगाने की इच्छा बढ़े?

भार्गव इस बात से बहुत खफा हैं कि अधिकतर कार मालिक अपनी कारों में अनुपयोगी सामान जैसे, काले शीशे, सुंदर बंपर और ग्रिल्स तथा टेलीविजन आदि लगवाते हैं। वह कहते हैं, "ये सब चीजें किसी भी सुरक्षा के प्रति सावधान रहने वाले देश में नहीं होनी चाहिए। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे यहां कारों के लिए ऐसे कोई नियम नहीं हैं। अतः इन सबको रोकने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता को कार के सही उपयोगों के बारे में जागृत करने के लिए हम कुछ फिल्में बना रहे हैं।" इनसे उन मारुति चालकों को कारों के रखरखाव और सही चालन की जानकारी मिलेगी।

—एस०एस०

Tulsi
ZAFRANI ZARDA
FLAVOURED CHEWING TOBACCO
00
DHARAMPAL SATYAPAL
THE ECO
NO 116
ence
res
शानो शौकत के ढंग... तुलसी ज़र्दा के संग
अनेकानेक वैरायटीज़ के
धर्मपाल सत्य

आप तो इतनी मेहनत करती हैं अपने परिवार की देखभाल के लिए. लेकिन आपकी सुख-सुविधा की फ़िक्र कौन करता है?

नया Godrej® 165 लीटर रेफ़्रिजरेटर

नये गोदरेज 165 लीटर रेफ़्रिजरेटर की डिज़ाइन आपकी सुविधा को ध्यान में रख कर ही की गयी है: तभी तो इसमें आपको मिलती है ज़्यादा जगह, ठीक वहां, जहां ज़रूरत है: सब्ज़ी ट्रे और दरवाज़े के पैनल में.

सब्ज़ी ट्रे और अंडों का रैक सबसे बड़ा —165 लीटर रेफ़्रिजरेटरों में

गोदरेज सब्ज़ी ट्रे में काफ़ी चीज़ें अँटती हैं और सब्ज़ियाँ ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहती हैं.

दरवाज़े के पैनल में 15 अंडे तक रखे जा सकते हैं— दूसरे रेफ़्रिजरेटरों से ज़्यादा. आपके परिवार की रोज़-रोज़ की ज़रूरतें पूरी करने में आपका सच्चा सहायक है नया गोदरेज.

एकमात्र 165 लीटर रेफ़्रिजरेटर जिसमें 10 बड़ी बोतलें रखी जा सकती हैं.

इसलिए अब बार-बार बोतलें भर कर रखने का झमेला खत्म.

उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल : ऊपर-नीचे किये जा सकनेवाले शेल्फ़

अलग-अलग आकार के कटोरे या डिब्बे रखने के लिए नये गोदरेज के शेल्फ़ आसानी से ऊपर-नीचे किये जा सकते हैं.

नयी तकनीक तेज़ी से ठंडा करे— बिजली की बचत करे

नया, मज़बूत व बिजली बचानेवाला कार्यक्षम कंप्रेसर तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडोंवाला पॉलीयूरीथेन इंसुलेशन रेफ़्रिजरेटर को तेज़ी से ठंडा करते हैं.

उन्नत तकनीक के फलस्वरूप बिजली कम खर्च होती है और आपका बिजली बिल काफ़ी घट जाता है.

और, सबके ऊपर बेहतरीन फ़िनिश

एपॉक्सी पाउडर कोटेड फ़िनिश के कारण इसके बाहरी भाग पर खरोंच-निशान पड़ने का डर नहीं तथा यह ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा आकर्षक बना रहता है.

अब रह जाती है केवल एक बात, और उसका फ़ैसला गोदरेज ने आप पर छोड़ रखा है. यानी कि नया गोदरेज खरीदने की बात. ताकि आप अपने परिवार की और बेहतर देखभाल कर सकें.

Godrej®

नया गोदरेज रेफ़्रिजरेटर.
हर व्यस्त गृहिणी के लिए बेहद ज़रूरी.

HTA-1645

Jantushree
पटुश्री
JN JENSON & NICHOLSON

राष्ट्रपति वेंकटरमण दक्षिण तृतीय एशियायी खेल के उद्घाटन के अवसर पर

छाया: ए० कुमार

आगे-ही-आगे: मार्चपास्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पी०टी० उषा

दक्षिण एशियायी खेल

भारत का वर्चस्व बना रहा

युवभारती क्रीड़ांगन में पहले उपनिषद के स्वर और फिर विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर का लोकप्रिय गीत 'आनंदलोके मंगलालोके विराज सत्यसुंदर' गूंज उठा। इलेक्ट्रानिक स्कोर बोर्ड पर उस समय ठीक ४ बजकर १० मिनट हुए थे। उसी समय स्कोर बोर्ड पर भारत का मानचित्र उभरा। दर्शक-दीर्घा लबालब भरी हुई थी। ठीक ४ बजकर ३८ मिनट पर भारत के राष्ट्रपति आर० वेंकटरमण ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर तृतीय दक्षिण एशियायी खेलों (सैफ गेम्स) के शुभारंभ की घोषणा कर दी। क्रम से भूटान, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका और भारत के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। उस समय स्कोर बोर्ड पर एक-एक कर इन देशों के मानचित्र उभरने लगे थे।

मूल प्रेरणा: २८ सितंबर, १९८१ को पश्चिम जर्मनी के बादेन-बादेन में ११ वें ओलंपिक सम्मेलन के अवसर पर होटल बादीचेर में बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भारत [illegible]निधियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई, [illegible] आपसी

HTA-1846

फ़्लेअर के संग, उमंग ही उमंग!
UNIVERSAL BOXING EQUIPMENT
8 OZ
12 OZ
UNIVERSAL BOXING EQUIPMENT
GOLDEN'S
FLAIR
DELUXE FILTER
CIG. LENGTH 69 mm
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Govan/FDF/B/1/87/HN
वैधानिक चेतावनी : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

घनिष्ठता और सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया क्रीड़ा समारोह शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। उसी का वास्तविक रूप है यह सैफ गेम्स। बादेन-बादेन के होटल के उस कमरे में जो स्वप्न एक प्रस्ताव के रूप में था, २६ नवंबर, १९८१ को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबिंदर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के अशोका होटल में वह साकार हुआ। 'सैफ' संगठन बना। इसका पूरा नाम है-साउथ एशियन फेडरेशन, यानी एस०ए०एस०एफ०।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस कार्यसूची को लेकर सैफ संगठन का जन्म हुआ था, आज उसे उसने काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। खेल के मैदान में जिस भ्रातृत्व का उदय हुआ है, आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। शुरू में सैफ संगठन के सदस्य थे—भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। बाद में उसमें भूटान और मालद्वीप के शामिल हो जाने से उसके सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर सात हो गयी। अफगानिस्तान की टीम भी खेलों में भाग लेने आयी थी पर उसे इजाजत नहीं मिली।

कलकत्ता में : काठमांडू (नेपाल) और ढाका (बंगलादेश) के बाद तृतीय सैफ गेम्स भारत के गौरवशाली महानगर कलकत्ता में २० नवंबर, १९८७ को आयोजित हुए।

तृतीय सैफ गेम्स में भाग लेने वाले सात देशों के सौहार्द्र और भातृत्व के बंधन को सुदृढ़ करने लिए २० लाख क्रीड़ा-प्रेमियों की मानव-शृंखला ने पवित्र मशाल को ९५ किलोमीटर की दूरी तय कर बनगां सीमा से नेताजी इनडोर स्टेडियम तक पहुंचाया। ढाका से 'सैफ' खेलों की मशाल लायी गयी। बंगलादेश के क्रीड़ामंत्री जमाल हैदर ने सीमा पर मशाल को पश्चिम बंगाल के क्रीड़ामंत्री सुभाष चक्रवर्ती को सौंपी। फिर रिले सिस्टम से उस मशाल को प्रसिद्ध एथलीट और धावक कलकत्ता तक ले आये।

इस समारोह में भारत के २३०, पाकिस्तान के १३३, भूटान के ४७, नेपाल के ११९, मालद्वीप के २१, श्रीलंका के ९५ और बंगलादेश के १२८ खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रथम और द्वितीय सैफ गेम्स की तुलना में इस बार प्रतियोगियों की संख्या अधिक रही। इस बार सैफ गेम्स में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, फुटबाल, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी, टेबिल टेनिस, डेकाथलान, पैदल और मैराथन रेस आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं थीं। प्रतियोगियों की कमी के कारण महिलाओं के टेबिल टेनिस, डेकाथलन, पैदल और मैराथन रेस को निकाल देना पड़ा। आठ दिनों के तृतीय सैफ गेम्स में स्प्रिंट क्वीन पी०टी० उषा ने सुनहला रिकार्ड कायम किया और सैयद अब्राहम का रिकार्ड तोड़ा। कुल ९१ स्वर्णपदक पाकर इस बार भी भारत सोना जीतने में शीर्ष स्थान पर रहा। पाकिस्तान १६ स्वर्णपदक पाकर दूसरे स्थान पर रहा। श्रीलंका को ४ स्वर्णपदक मिले। फुटबाल में भारत को चैंपियनशिप मिली। तैराकी में भारत ने अपना एकाधिकार सिद्ध किया।

—गुरु[illegible] महांति

सैफ गेम्स

	कहां ?	कब ?	भाग लेने वाले देश	प्रतियोगिताएं
प्रथम—	काठमांडू नेपाल	१७-२३ सितंबर, १९८४	भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालद्वीप, श्रीलंका, पाकिस्तान	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, भारोत्तोलन, तैराकी
द्वितीय—	ढाका बंगलादेश	२०-२६ दिसंबर, १९८५	भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालद्वीप, श्रीलंका, पाकिस्तान	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, फुटबाल, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी
तृतीय—	कलकत्ता भारत	२०-२७ नवंबर, १९८७	भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालद्वीप, श्रीलंका, पाकिस्तान	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, फुटबाल, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी, टेबिल टेनिस, डेकाथलन, पैदल चलना, मैराथन रेस (महिलाओं के लिए टेबिल टेनिस, डेकाथलन, पैदल चलना और मैराथन रेस प्रतियोगिताएं नहीं हो सकीं)

प्रथम सैफ गेम्स १९८४ : पदक

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
भारत	४४	२८	१६	८८
श्रीलंका	७	११	१९	३७
पाकिस्तान	५	३	२	१०
नेपाल	४	१२	८	२४
बंगलादेश	२	८	१३	२३
भूटान			१	१
मालद्वीव			१	१

द्वितीय सैफ गेम्स १९८५ : पदक

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
भारत	४६	२९	१४	१०९
पाकिस्तान	१६	११	३	३८
बंगलादेश	९	१६	३४	५९
श्रीलंका	२	४	७	१३
नेपाल	१	५	१२	१८

भारत सैफ गेम्स में किसको कितने पदक मिले ?

	भारत	पाकिस्तान	श्रीलंका	बंगलादेश	नेपाल	भूटान
स्वर्ण	९१	१६	४	३	२	०
रजत	४५	३६	८	१९	७	१
कांस्य	१९	१३	२३	५२	३३	५
कुल	१५५	६५	३५	५४	४२	६

साक्षात्कार/ब०व० कारंत

फैसले के बाद कर्नाटक जाकर काम करूंगा

बारह-तेरह वर्ष की आयु में वह घर से भाग निकले। घर से भागना उनके घर व गांववालों के लिए कोई अनहोनी घटना या नयी बात नहीं थी। गांव से इसके पहले और भी बच्चे फटेहाल जिंदगी, भूख और गरीबी से तंग आकर शहरों को भाग गये थे, जहां वे होटलों में कप-प्लेट धोने का या कोई और काम करके पेट भरने लायक कमा लेते थे।

यह किस्सा है कर्नाटक प्रांत के दक्षिण कन्नड़ के मेची गांव का और कहानी है, ख्यातनाम रंगकर्मी ब०व० कारंत की। अन्य बच्चों की भांति बालक कारंत के भागने पर उनके माता-पिता ने उनकी कोई सुध नहीं ली। पिता ने सोचा, चलो अपनी दो जून की रोटी के लायक कुछ-न-कुछ कमा रहा होगा। पिता का सोचना सही था, मगर बालक कारंत ने किसी होटल या दूकान के बजाय अलग रास्ता पकड़ा था। वह गांव से भागे, तो शहर जाकर नामी-गिरामी गुब्बी थियेट्रिकल कंपनी में भरती हो गये और इस प्रकार शुरू हुआ एक रंगकर्मी का लंबा, संघर्षमय और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा जीवन।

गोरे चिट्टे बालक कारंत ने घर से भागने के बाद डेढ़-दो साल तक अपने पिता को कोई पत्र नहीं लिखा। करीब डेढ़-दो साल बाद पिता के साथ पत्राचार का सिलसिला प्रारंभ हुआ, लेकिन गांव लौटना उनके नसीब में न था। उनके पैरों में शनीचर था, लिहाजा वह रंगकर्म, हिन्दी सीखने और कुछ कर गुजरने के फेर में पता नहीं कहां-कहां भटके। बचपन में घर से भागे तो थियेटर किया, फिर हिन्दी प्रचारक बने, हिंदी प्रचारकों को खोज-खोज कर हिंदी सीखी, गोवा जाकर सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गये। फिर स्कूल में मास्टरी की, काशी में रहकर हिंदी साहित्य में एम०ए० किया, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संगीत की शिक्षा ली। तीनु लोक से न्यारी काशी छोड़ी तो दिल्ली पहुंच गये और नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। उन्हीं दिनों ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, मोहन महर्षि, रामगोपाल बजाज, दिनेश ठाकुर आदि के सहयोग से 'दिशांतर' के बैनर तले अनेक नाटक खेले, जिन्हें सर्वत्र प्रशंसा मिली।

गिरीश कर्नाड कारंत के पुराने मित्र हैं। विभा प्रकरण की खबर लगते ही वह अपने दोस्त से मिलने बंबई से भोपाल आये थे। तब उनसे कारंत के बारे में चर्चा चली थी। ७०-७१ की बात है। कारंत ने कर्नाटक में इडीपस, संक्रांति और चो कुमार स्वामी नामक तीन नाटकों का निर्देशन किया था। कर्नाड ने कारंत के निर्देशन में 'इडीपस' में काम किया था। वह अनुभव कर्नाड आज तक नहीं भूले। कर्नाड इन नाटकों को कन्नड़ रंगमंच के इतिहास की युगांतरकारी घटना मानते हैं। उन्होंने कहा था, "कारंत के इन नाटकों ने कन्नड़ रंगमंच को नया मोड़ व नयी दिशा दी।" कारंत और कर्नाड का साथ आगे भी रहा। कर्नाड की फिल्म 'काडू' में कारंत कला निर्देशक थे और संगीत भी उन्होंने ही दिया था।

कन्नड़भाषी कारंत को हिंदी से बहुत अनुराग है। हिंदी सीखना और चरखा चलाना उनके लिए राष्ट्रसेवा का पर्याय रहा है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा अहम पहलू है—रंगकर्म से गहरा भावनात्मक लगाव। रंगकर्म उनके लिए मिशन भी है, प्रोफेशन भी है और व्यसन भी। रंगकर्म के प्रति उनकी आसक्ति इतनी गहरी है कि कारागार भी उन्हें नाट्यशाला प्रतीत हुआ। जेल के अपने अनुभवों के आधार पर वह कहते हैं, "जेल चरित्रों का लंबा और बहुरंगी काफिला है।"

१९७३ में कारंत अशोक वाजपेयी के आमंत्रण पर भोपाल आये और नाटक वर्कशाप किया। इस बीच उन्हें प्रख्यात लेखक शिवराम कारंत का पत्र मिला कि एक निर्माता उनके उपन्यास 'चोमन्ना डुडि' पर फिल्म बनाना चाहते हैं और अगर वह चाहें तो फिल्म का निर्देशन कर सकते हैं। १९७४ में फिल्म पूरी हुई और उसे तीन नेशनल अवार्ड मिले। 'चोमन्ना डुडि' खूब चली। फिल्म को लेकर कारंत पश्चिम बर्लिन गये। कार्लोवारी में फिल्म को बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला।

कारंत ने विश्व के महत्वपूर्ण क्लासिक नाटकों का हिंदी, कन्नड़, गुजराती व पंजाबी भाषाओं में निर्देशन और कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत व कन्नड़ नाटकों का हिन्दी और उर्दू में अनुवाद भी किया है। जर्मनी, हंगरी, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, पोलैंड, चोकोस्लोवाकिया, रूस और अमरीका सहित अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं कीं। आस्ट्रेलिया में रंगकार्यशाला संचालित की और 'हयवदन' का निर्देशन किया। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार १९७६-७७, रंगकर्म के लिए एफ ए आई पुरस्कार, १९७६ में 'काडु' फिल्म में संगीत निर्देशन के लिए पुरस्कार। १९७६ व १९७९ में श्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पुरस्कृत। कन्नड़ भाषा में रंग-निर्देशन के लिए १९८३ में पुरस्कृत हुए। १९७७ से १९८१ तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व १९८१ से १९८६ तक रंगमंडल, भारत-भवन के निर्देशक रहे। १९८४ से १९८६ तक म०प्र० फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और १९८२ से १९८६ तक भारत-भवन, भोपाल के न्यासी।

कारंत अब रंगमडल में नहीं हैं, लेकिन रंगमंडल से उनका मोह बरकरार है। रंगमंडल के लोग उन्हें फ्रेंड, फिलासफर व गाइड की तरह याद करते हैं। विभा-प्रसंग रंगमंडल से जुड़े सभी लोगों के लिए एक हादसे की तरह है। और कारंत—कारंत को अलादत के फैसले का इंतजार है। वह कहते हैं, "अगर यह हादसा नहीं होता, तो मैं रामकृष्ण हेगड़े के आमंत्रण पर कर्नाटक में होता।"

अदालत का फैसला कुछ भी हो, परंतु यह सच है कि इस हादसे के कारण कारंत को सर्वथा अलग अनुभव के दौर से गुजरना पड़ा है। हादसे के बाद उन्होंने शायद ही किसी लेखक या पत्रकार से खुलकर बातचीत की होगी, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने 'माया' के लिए युवा कवि रमेश अनुपम से दो बैठकों में लंबी बातचीत की। बातचीत में उन्होंने पीछे मुड़कर अपने बचपने, कैशोर्य, जवानी के संघर्ष, रंगमंच व अध्ययन के सिलसिले में भागदौड़ और रंगकर्म से अपनी गहरी आसक्ति के असमाप्त दौर के दिनों को जी भर कर निहारा है। प्रस्तुत हैं, वार्ता के प्रमुख अंश :

माया :आप रंगमंच से कैसे जुड़े ?

कारंत : मेरे जन्म से पूर्व ही दक्षिण कन्नड़ जिले में या मेरे जन्म स्थान के आसपास यक्षगान जैसा लोक नाटक रचा-बसा हुआ था। मैं पहले से ही उसका एक हिस्सा बन चुका था और उससे जुड़े रहना ही मेरी नियति बन चुकी थी। मैं अकसर लोगों से या रंगकर्मियों से कहा करता हूं कि रंगमंच मेरे लिए एक शौक भी है, एक मिशन भी है और प्रोफेशन भी। अब मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि रंगमंच मेरे लिए एक व्यसन भी है।

माया : रंगमंच से जुड़ने की इच्छा के पीछे कौन से कारण थे ?

कारंत : अपने स्कूल के दिनों में ही मैं रंगमंच का खिलौना बन चुका था। स्कूल में कोई भी नाटक हो, मैं बच नहीं पाता था, क्योंकि मैं गाता अच्छा था और उछलकूद भी खूब किया करता था। नाटक की यह मूल सामग्री बचपन से ही शायद मेरे भीतर मौजूद थी, लेकिन वस्तुतः मेरे रंग-जीवन का प्रारंभ कर्नाटक की प्रसिद्ध गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में जाने के पश्चात हुआ। एक तरह से मुझे गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में ही रंगकर्म का सही सस्कार मिला।

माया : गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में कब और कैसे गये ?

कारंत : मैं अपने गांव के प्रायमरी स्कूल में पढ़ा करता था। उन दिनों कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश में गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी का बहुत नाम था। उस समय गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में लगभग डेढ़ सौ लोग काम करते थे। सुना है कि जब कम्पनी अपनी चरम प्रसिद्धि पर थी (१९३०-४० के आसपास), तो इसमें तीन सौ लोग काम करते थे। मुझे आज भी याद है कि उन दिनों मेंगलूर जिले में गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी का एक नाटक चल रहा था। मेंगलूर हमारे गांव से तीस किमी० दूर था। हम (पिताजी, चाचाजी और मैं) एक किराये की सायकिल लेकर रात में नाटक देखने के लिए मेंगलूर गये। वहां हमने 'कृष्ण लीला' नामक नाटक देखा, जो कम्पनी का बहुत लोकप्रिय नाटक था। इसमें सैंतीस ट्रांसफर सीन थे। अद्‌भुत दृश्यावली थी। तभी से गुब्बी कम्पनी का आकर्षण मेरे अबोध मस्तिष्क पर अंकित हो गया था। हम लोग बहुत गरीब थे। घर की हालत बहुत दयनीय थी। मुझे पिताजी केवल पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ा पाये थे। बाद में गांव के जमींदार की कृपा से मैं आठवीं कक्षा तक पढ़ पाया। मैं जमींदार के यहां रहकर उनके बच्चों को पढ़ाता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। आठवीं कक्षा के बाद जमींदार की कृपा-दृष्टि भी एक तरह से समाप्त हो गयी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं? मैं आगे पढ़ना चाहता था पर घर की गरीबी के कारण किसी भी दृष्टि से संभव नहीं था। उस समय हमारे गांव के बहुत से लड़के घर की गरीबी से तंग आकर बम्बई या बेंगलूर भाग जाते थे। मेरे सामने भी घर से भागने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चूंकि, अभिनेता बनने का प्रबल आकर्षण बचपन से मेरे मन में था और गुब्बी थियेट्रिकल कंपनी का आकर्षण भी मेरे मन में जबरदस्त रूप से घर कर चुका था, इसलिए मैं घर से भागकर सीधे मैसूर पहुंचा। वहां उस समय गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी का नाटक चल रहा था। मैं बहुत अच्छा गाता था और मेरा रंग भी गोरा था, इसलिए गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में मुझे भरती कर लिया गया। यह घटना १९४२ के आसपास की है। मेरी उम्र उस समय लगभग बारह-तेरह वर्ष की रही होगी। मुझे वहां सब 'छोटा बेबी' के नाम से पुकारते थे। मेरे गोरे रंग और अच्छा गाना गाने की योग्यता के चलते मुझे वहां लड़कियों का रोल भी करने के लिए दिया जाता था। बाद में मुझे कृष्ण और नारद की भूमिका मिलने लगी थी। अब मुझे याद करके हंसी आती है कि एक नाटक के पहले दृश्य में मैं देवकी बनता था और अंतिम दृश्य में कंस को मारनेवाला कृष्ण भी। देवकी की भूमिका में दो संवाद और दो गाना होता था और कृष्ण की भूमिका में पांच—छह संवाद तथा चार गाने थे। सबसे छोटा होने के कारण नारद मुनि की भूमिका भी मुझे ही मिलती थी। भक्त मार्कण्डेय मेरा एक प्रसिद्ध नाटक था। इसमें मैं भक्त मार्कण्डेय बनता था। इससे मुझे बहुत प्रशंसा मिली। उस समय गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में मुझे खाने-पीने के अलावा मासिक वेतन के रूप में बारह रुपए मिलते थे। मेरी तनख्वाह में दस रुपए की वृद्धि हुई, क्योंकि मैं हारमोनियम बजाना (पांव से बजाया जाने वाला) सीख चुका था। छह-सात वर्ष बाद गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी कुछ दिनों के लिए बन्द हो गयी।

जीवंत अभिनय : कारंत एक भूमिका में

> **भारत-भवन और रंगमंडल के इन पांच-छह वर्षों को पीछे मुड़कर देखने पर मैं स्वयं अपने आपको काफी छोटा महसूस करता हूं। अपना ही किया हुआ सब मुझे चुनौती देता हुआ-सा लगता है। यह भी सच है कि कारंत आयेगा और जायेगा, पर रंगमंडल अपने बलबूते पर जिन्दा रहेगा।**

माया : गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी बन्द होने के बाद क्या आप घर लौट गये थे ?

कारंत : नहीं, मैं वापस घर नहीं लौटा। शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो कि गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी बन्द होने के बाद मैं हिंदी प्रचारक बन गया था।

माया : रंगमंच से अचानक हिंदी-प्रचार का विचार कैसे आ गया ?

कारंत : असल में गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में ही व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ एक त्रासद तथा सामाजिक जींवन में एक भावुक घटना घटित हो गयी। त्रासद घटना यह कि दो-ढाई वर्ष बाद ही मेरी आवाज फटने लगी थी। शायद उम्र बढ़ने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन कम्पनी में यह स्थिति लड़कों के लिए बहुत चिंताजनक मानी जाती थी, क्योंकि बड़े रोल के लिए हम छोटे पड़ जाते थे और छोटे रोल के लिए (आवाज के फटने के कारण) हमें उपयुक्त नहीं समझा जाता था। ऐसे में कम्पनी के दूसरे लड़कों की तरह मुझे भी प्रमुख भूमिकाएं मिलनी बन्द हो गयी थीं। इसकी जगह सिपाही, चंवरधारी और चर जैसी छोटी-मोटी भूमिकाएं मिलने लगी थीं। यह स्थिति मेरे लिये बहुत दुखदायी थी। उन्हीं दिनों आजादी की लड़ाई भी अपनी चरम सीमा पर थी। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' वाला आन्दोलन १९४२ में शुरू हो चुका था। कांग्रेसी नेताओं का कम्पनी में आना-जाना शुरू हो चुका था। हम सबके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। शायद इसीलिए उस समय मेरे मन में अभिनेता के साथ-साथ नेता बनने की ललक भी पैदा हो चुकी थी। लेकिन उस उम्र में मैं नेता कैसे बनता? जेल जाना भी मेरे लिए असंभव था। हालांकि हिंदी प्रचारक बनने के बाद मैंने गोवा जाकर एक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप मुझे दो तीन दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा (यह घटना आजादी के बाद की है)। उस समय गांधीजी के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का बोलबाला बहुत था। कांग्रेसी नेताओं के साथ मैं बहुत से हिंदी प्रचारकों को भी कम्पनी में आते-जाते देखा करता था। शायद इसी के बाद मुझे भी लगने लगा था कि मुझे भी हिंदी प्रचारक बनना चाहिए। तब मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। आजादी की लड़ाई में मैं,

छोटा सा ही सही, अपना योगदान देना चाहता था। मुझे लगा कि राष्ट्रभाषा सीखना और चरखा चलाना भी एक तरह से राष्ट्र की सेवा करना ही है। मैंने हिंदी सीखना और चरखा चलाना प्रारभ कर दिया। हिंदी सीखने के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ती गयी। उस समय कम्पनी को अलग-अलग शहरों में जाकर नाटक करना पड़ता था। कम्पनी जब भी एक शहर से दूसरे शहर में नाटक करने के लिए अपना कैम्प डालती थी, मैं सबसे पहले किसी हिंदी प्रचारक को ढूंढ़ता था और उससे हिंदी सीखता था। इसके पश्चात मुझे लगा कि हिंदी की परीक्षाएं भी पास करनी चाहिए। कम्पनी में रहते-रहते ही मैंने दक्षिण मध्य हिंदी प्रचार सभा की चार परीक्षाएं (प्रथमा, मध्यमा, राष्ट्रभाषा और प्रवेशिका) उत्तीर्ण कर ली थीं। सौभाग्य से कम्पनी के मालिक वीरण्णाजी ने शुरू से मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया। वीरण्णाजी के सहयोग का ही परिणाम था कि मैंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की अंतिम परीक्षाएं विशारद, प्रवीण और प्रचारक भी पास कर ली थीं। कम्पनी बन्द हुई, तो किसी दूसरी कम्पनी में भटकने के बदले मैंने हिंदी प्रचारक बनकर राष्ट्र की सेवा करना महत्वपूर्ण समझा। अब मुझे लगता है कि अगर कम्पनी के मालिक वीरण्णाजी ने मेरी मदद नहीं की होती, तो शायद मैं कभी भी हिंदी की परीक्षाएं पास नहीं कर पाता और न ही हिंदी प्रचारक बन पाता।

माया: हिन्दी प्रचारक से रंगमंच में पुनर्प्रवेश के पीछे कौन से आकर्षण थे?

कारंत: हिंदी प्रचारक का काम करने के पश्चात मैं बेंगलूर के मारवाड़ियों द्वारा संचालित स्कूल हिंदी माध्यमिक बालक बस्ती में हिंदी का अध्यापक बन गया था। वहां मैं चार वर्षों तक रहा। किन्तु इन चार वर्षों में रंगमंच के प्रति जो मेरा आकर्षण था, वह यथावत रहा। मैं कम्पनी की तरह प्रोफेशनल थियेटर तो नहीं चला सकता था, किन्तु शौकिया रंगमंच से मैं अवश्य जुड़ा रहा। गुब्बी थियेट्रिकल के अनुभवों के कारण मै उस समय अंधों में काने राजा की तरह था। स्कूल में रंगमंच की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज्यादा थी। मैं स्कूल के बच्चों को लेकर नाटक करने के लिए भी हिंदी के नाटक करता था। गुब्बी थियेट्रिकल के अनुभवों के कारण स्टेज पर परदा लगाने से लेकर मेकअप करना, संगीत का प्रभाव देना आदि मैं जानता ही था। मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन के दौरान ही मैंने साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा (साहित्य रत्न) की परीक्षाएं पास कर ली थीं। साहित्य सम्मेलन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने महसूस किया कि जब तक विश्वविद्यालय की मोहर नहीं लग जाती, तब तक मेरी सारी शिक्षा-दीक्षा बेकार है। इसलिए मैंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आवेदन-पत्र दिया और [illegible] की बात यह है कि इस परीक्षा से मेरा दूसरा जन्म हुआ।

माया: वह कैसे?

कारंत: असल में मुझे अपने जन्म की सही तारीख पता नहीं थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से परीक्षा देने के लिए जन्म की तारीख तय कर ली, १९ सितंबर, १९२९। इस पर एक गजटेड आफीसर की मोहर लग चुकी है, इसलिए अब यही मेरी जन्म-तिथि बन चुकी है। इसे मैं अपना दूसरा जन्म ही मानता हूं।

माया: मैट्रिक के बाद?

कारंत: मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मैंने मारवाड़ी स्कूल में नौकरी करते हुए ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बी०ए० की परीक्षा भी प्रायवेट छात्र के रूप में पास कर ली थी। बी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे यह लगने लगा था कि जब तक किसी हिंदी प्रदेश में रहकर हिंदी न सीख लूं, तब तक मेरा हिंदी का ज्ञान अधूरा ही है, इसलिए बी०ए० करने के बाद मैं बड़े नाटकीय ढंग से बेगलूर से गायब होकर बनारस पहुंच गया।

प्रतिभा का प्रस्फुटन: गुब्बी कंपनी के बाल कलाकार कारंत

अब मुझे याद करके हंसी आती है कि एक नाटक के पहले दृश्य में मैं देवकी बनता था और अंतिम दृश्य में कंस को मारनेवाला कृष्ण भी। देवकी की भूमिका में दो संवाद और दो गाना होता था और कृष्ण की भूमिका में पांच-छह संवाद तथा चार गाने थे। सबसे छोटा होने के कारण नारद मुनि की भूमिका भी मुझे ही मिलती थी।

माया: बनारस के इस नाटकीय प्रस्थान के पीछे क्या बनारस का धार्मिक आकर्षण आपको खींच रहा था?

कारंत: बनारस मैं पुण्य कमाने के लिए बिलकुल ही नहीं गया था। दरअसल, मुझमें हिंदी प्रदेश में रहकर हिंदी सीखने की इच्छा बलवती हो गयी थी। मैं बनारस में रहकर हिंदी साहित्य में एम०ए० करना चाहता था, इसलिए मैं खाली हाथ बनारस पहुंच गया। अर्थाभाव की 'समझ' ने मेरी मदद की। मैंने बनारस पहुंचकर अपने सारे परिचितों और अपनी कम्पनी के मालिक वीरण्णाजी को पत्र लिखकर एम०ए० करने की इच्छा प्रकट करते हुए आर्थिक सहायता मांगी। काशी की महिमा! पूरे दो वर्ष तक मुझे हर महीने नब्बे रुपए से लेकर सौ रुपए तक आर्थिक सहायता मिलने लगी।

माया: बनारस प्रवास में ही तो शास्त्रीय संगीत से भी आपका रिश्ता बनना शुरू हुआ?

कारंत: संगीत के प्रति मेरा रुझान तो बचपन से ही था। गुब्बी थियेट्रिकल कम्पनी में यह रुझान और भी बढ़ा। बनारस के संगीत महाविद्यालय में उस समय पं० ओंकार नाथ ठाकुर प्रिंसिपल थे। उनका उस समय बहुत नाम था। मैंने पं० ओंकार नाथ ठाकुर से संगीत की शिक्षा ली।

माया: और थियेटर?

कारंत: बनारस में भी रंगमंच से मेरा संबंध नहीं टूटा। विश्वविद्यालय के 'कर्नाटक संघ' में, महाविद्यालय, छात्रावास सभी जगह नाटक या किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में मेरी बहुत मांग होती थी और मैं भी वहां अपनी नाक घुसेड़ने में कोताही नहीं करता था।

एम०ए० अंतिम वर्ष में मैंने 'लय तत्व और हिंदी कविता' पर लघु शोध-प्रबंध लिखा, किन्तु एम०ए० करने के पश्चात पी०एच०डी० के लिए मैंने 'भारतीय रंगमंच और हिंदी नाटक' जैसा विषय चुना। दो वर्ष तक इस पर काम भी किया। पी०एच०डी० करते समय मुझे यह महसूस हुआ कि रंगमंच के सैद्धांतिक तथा तकनीकी दोनों पक्षों का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए बनारस में चार साल तक रहने के बाद वापस कर्नाटक न जाकर मैं दिल्ली पहुंच गया और वहां मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन ले लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्ययन किया तथा निर्देशन में विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे १९६२ का बेस्ट आल राउंड स्टूडेंट का सम्मान भी मिला।

माया: फिर बनारस वाली पी०एच०डी०?

कारंत: पी०एच०डी० का काम तो एक तरह से खटाई में पड़ गया। हालांकि इसके लिए मुझे विश्वविद्यालय की ओर से ९ वर्ष का समय

मिला था, पर अब पी०एच०डी० करने के लिए मेरे पास समय कहां था ?

माया : नाट्य विद्यालय से आप कर्नाटक लौटे या बनारस ?

कारंत : लगता है, तब कर्नाटक वापस न लौटना ही मेरी नियति बन चुकी थी। हिंदी भाषा, हिंदी रंगमंच और हिंदी साहित्य से मैं पूरी तरह से जुड़ गया था। दिल्ली में अपनी रंग गतिविधियों को परिचालित करने के लिए मैंने सरदार पटेल हायर सेकेंड्री स्कूल में अध्यापकी कर ली, पर मैं वहां कहने को ही हिंदी का अध्यापक था। मेरा काम तो वहां बच्चों को लेकर नाटक करना था। वहां रहकर, बच्चों के साथ काम करते हुए रंगमंच और हिंदी रंगमंच इन दोनों को समझने का और नये-नये प्रयोग करने का अवसर मुझे बहुत मिला।

माया : स्कूल के बाहर आपकी रंग गतिविधियां क्या थीं ?

कारंत : उन दिनों दिल्ली में बिताये सात वर्ष मेरे लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण के वर्षों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। उन सात वर्षों में मुझे अपने को आजमाने का, रंग-दृष्टि से सम्पन्न होने (बनाने) का, अपनी कमजोरियों को जानने-समझने का भरपूर अवसर मिला था। एक तरह से मेरे आगे के काम के लिए यह प्रयोग और प्रक्रिया का हिस्सा था। मैं दिल्ली में एक ओर स्कूल के बच्चों के साथ काम करता था और दूसरी ओर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर 'दिशांतर' नामक एक नाट्य संस्था भी चलाता था। 'दिशांतर' में मेरे अलावा ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, रामगोपाल बजाज, बी०एम० शाह, दिनेश ठाकुर, मीना विलियम्स, वामदेव, प्रेमा कारंत, विश्व मोहन बडोला, मोहन महर्षि जैसे दिल्ली के प्रमुख युवा रंगकर्मी शामिल थे। हम लोगों को उस समय रंगमंच से कुछ कमाने की चिंता नहीं थी। चूंकि हम सब लोग अलग-अलग जगहों पर नौकरी भी किया करते थे, इसलिए थियेटर हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं था। हम सब तन-मन लगाकर 'दिशांतर' में काम करते थें। उस समय 'खामोश : अदालत जारी है' तथा 'आधे-अधूरे' को हमने पहली बार 'दिशांतर' के माध्यम से प्रस्तुत किया था। हमारे 'हयवदन' और 'तुगलक' जैसे नाटकों की प्रस्तुति की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी। 'दिशांतर' के अलावा मैं वर्ष में एक बार कर्नाटक जाकर भी वहां के वर्कशाप में काम करता था। इस सन्दर्भ में मैं आद्य रंगाचार्य का श्रद्धा से स्मरण करता हूं। उनकी अथक कोशिशों से ही कन्नड़ रंगमंच को भारतीय रंगमंच से जोड़ने की दृष्टि मिली। उस वर्कशाप ने कन्नड़ के प्रमुख रंगकर्मियों को ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा देश के कई शीर्ष रंगकर्मियों को भी इस वर्कशाप में आमंत्रित किया। मैं उस वक्त तक अपने आपको इस वर्कशाप के योग्य भी नहीं मानता था। इसी दरम्यान कल्चर एक्सचेंज के तहत मुझे पूर्वी यूरोप के पांच देशों में (पूर्वी बर्लिन, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया और बल्गारिया) जाने का अवसर मिला। इस तरह मैं १९७०-७१ तक दिल्ली में ही रहा। १९७०-७१ में एक दुर्घटना हो गयी, जिसके फलस्वरूप मुझे कर्नाटक वापस लौटना पड़ा। वह दुर्घटना थी 'वंशवृक्ष' फिल्म बनाने की।

माया : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे ख्यात ड्रामा स्कूल के निर्देशक पद को छोड़कर आप मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश के नये-नये बने रंगमंडल में कैसे आ गये ?

कारंत : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में निदेशक के पद पर काम करते हुए यह महसूस होने लगा था कि मैं शायद इस स्कूल की प्रतिष्ठा के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो भी महत्वाकांक्षाएं या योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित कर पाने में या नयी संभावनाओं को खोज पाने में कहीं पिछड़ रहा हूं। अलकाजी के जाने के बाद इस संस्था की गरिमा को बनाये रखना मेरे लिए सचमुच एक कठिन कार्य ही था। मैं निर्देशक पद से त्याग पत्र देकर दो वर्ष तक पूरे देश में घूम-घूमकर व्यावसायिक रंग-मंडलियों का प्रदर्शन देखने और उसका अध्ययन करने का मन बना चुका था। उसी समय मध्यप्रदेश से अशोक वाजपेयीजी की ओर से रंगमंडल, भारत भवन में निर्देशक पद का आफर मुझे मिला। चूंकि रंगमंडल मध्यप्रदेश में शुरू ही हो रहा था। मुझे लगा कि मैं रंगमंडल में एक 'वैक्यूम' से काम प्रारंभ कर सकूंगा। इसलिए एक तरह से रंगमंडल में आकर मुझे अच्छा लगा।

चरित्र के साथ तादात्म्य : 'महानिर्वाण' में भाऊराव की भूमिका में कारंत

बुनियादी तौर पर सत्ता जड़ होती है, पत्थर के बुत की तरह। लेकिन कोई क्रियाशील व्यक्ति जब सत्ता की दीवार से अपना माथा टकराता है, तो सत्ता सक्रिय हो उठती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता कुछ भी करे, यह हमारा काम है कि हम सत्ता को उसकी असली औकात के बारे में बताते रहें।

माया : तों क्या आप यह मानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए आप पूरी तरह से एक असफल निर्देशक थे।

कारंत : मैं विश्लेषण करता हूं तो लगता है कि अलकाजी के जाने के बाद कोई भी वहां आता, तो तुलनात्मक दृष्टि से वह असफल ही साबित होता। मैं यह शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम ही था।

माया : क्या आपको लगता है कि रंगमडल में आने से पहले रंगमंडल को लेकर जो आपने सपना देखा था उसे आप पूरी तरह से साकार कर पाये हैं ? कहीं आप यहां भी अपने आपको एक असफल निर्देशक तो नहीं मानते ?

कारंत : हां, सपने पूरे हुए हैं अपेक्षा से ज्यादा, लेकिन त्रासदी यह है कि पूरे होने पर भी वे सपने मरे नहीं हैं, बल्कि नये रूप धारण कर पुराने सपनों को झुठला रहे हैं। भारत-भवन और रंग मंडल के इन पांच-छह वर्षों को पीछे मुड़कर देखने पर मैं स्वयं अपने आपको काफी छोटा महसूस करता हूं। अपना ही किया हुआ सब मुझे चुनौती देता हुआ-सा लगता है। यह भी सच है कि कारंत आयेगा और जायेगा, पर रंगमंडल अपने बलबूते पर जिन्दा रहेगा, जब तक कि भारत-भवन और रंगमंडल यह निर्णय न कर ले कि अब हमें काम नहीं करना है।

माया : शायद आपने रंगमंडल से भी त्याग पत्र देने का मन बना लिया था। अगर यह हादसा (विभा-कांड) नहीं हुआ होता, तो शायद आप पिछले वर्ष ही कर्नाटक चले जाते ?

कारंत : मैं एक जगह टिककर रहता ही कहां हूं। रंगमंडल में मैं पांच वर्ष रह गया था और रंगमंडल छोड़कर कर्नाटक लौटने का मन बना चुका था। उसी समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने मुझसे कहा कि आप कर्नाटक आकर रेपर्टरी (नाटक संस्था) शुरू कीजिये, हम हर संभव आपकी मदद करेंगे। मैंने भी उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

त्यागपत्र देकर कर्नाटक जानेवाला ही था कि यह हादसा (विभा कांड) हो गया। अब तो न्यायालय में निर्णय हो जाने के बाद ही मैं कर्नाटक जाकर रिपर्टरी का काम शुरू कर पाऊंगा।

माया: अगर न्यायालय से (विभा प्रकरण में) निर्णय जल्दी हो गया और आप बरी हो गये, तो कर्नाटक में कब से काम शुरू कर देंगे?

कारंत: तब तो अगले वर्ष जनवरी या मार्च से काम शुरू कर दूंगा। कर्नाटक में जनवरी में 'संक्रांति' तथा मार्च में 'युगादि' को शुभ दिन के रूप में माना जाता है। मैं 'संक्रांति' या 'युगादि' से कर्नाटक में रेपर्टरी का काम शुरू करना चाहूंगा।

माया: आपने 'वशवृक्ष' और 'चोमन्ना डुडि' जैसी श्रेष्ठ फिल्मों का निर्देशन किया है। क्या भविष्य में भी इस तरह की फिल्में बनाना पसंद करेंगे?

कारंत: मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि फिल्म बनाना मेरे लिए एक दुर्घटना की तरह रहा है। जिन फिल्मों का उल्लेख आपने किया है, उसके निर्देशन के पीछे आकस्मिकता ही थी, जबकि रंगकर्म मेरा अपना चरित्र रहा है, मेरी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम रहा है। आज तो सिनेमा जगत में कई बड़ी-बडी 'हस्तियां' मौजूद हैं और यह काम मेरे बिना भी चल सकता है। पर इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य में भी इस तरह के ऐक्सीडेंट हो सकते हैं, अर्थात मैं फिल्म बना सकता हूं।

माया: हिंदी थियेटर के वर्तमान स्तर को लेकर आप क्या सोचते हैं?

कारंत: हिंदी रंगमंच की सबसे बड़ी ट्रेजडी यह है कि हिंदी रंगमंच में दर्शकों की परम्परा ही नहीं है।

माया: अभी हाल में प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली ने 'माया' को दिये इंटरव्यू में कहा है कि कला को सर्वाधिक खतरा सरकार से है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

कारंत: बुनियादी तौर पर सत्ता जड़ होती है, पत्थर के बुत की तरह। लेकिन कोई क्रियाशील व्यक्ति जब सत्ता की दीवार से अपना माथा टकराता है, तो सत्ता सक्रिय हो उठती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता कुछ भी करे, यह हमारा काम है कि हम सत्ता को उसकी असली औकात के बारे में बताते रहें। मैं सत्ता के भीतर भी था और बाहर भी। जब तक हमें अपने जनतंत्र पर विश्वास है, तब तक सत्ता के भूत से कोई डर नहीं। भूत से क्या डरना?

माया: एक संवेदनशील कलाकार के रूप में आपने जेल को किस तरह देखा और अनुभव किया है?

कारंत: जेल स्वयं एक नाटक है। प्रवेश और प्रस्थान का स्थायी रंगमंच। यह मैं व्यंग्य में नहीं, बल्कि अपने अनुभव से कह रहा हूं। नाटक व रंगमंच को हम अगर चरित्रों का खजाना मानते हैं, तो जेल चरित्रों का लम्बा और बहुरंगी काफिला है।

माया: आप पर बहुत कुछ अनाप-शनाप और एक तरह से मनगढ़ंत कहानियां लिखी गयी हैं। क्या आप पत्रकारिता को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे?

कारंत: कबीर ने कहा था कि भाषा बहता नीर है और मैं कहता हूं 'पत्रकारिता' बहता नाला है, जिसमें साफ-गंदा दोनों तरह का पानी बहता रहता है, सह-अस्तित्व के साथ। मैं कृतज्ञ हूं, अखबारों का जिन्होंने मुझे बड़े श्रम से जिलाये रखा।

माया: एक अंग्रेजी साप्ताहिक में सत्यदेव दुबे ने अपने एक लेख में आपको मीडियाकर ही घोषित कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

कारंत: मैं भी कालिदास और टैगोर के बाद एक जीनियस की खोज में लगा हूं। हां, पक्की बात है कि वह जीनियस न ब॰व॰ कारंत है, न सत्यदेव दुबे। फिर भी मन की बात कहूं, सीखचों के पीछे रहनेवाले एक मीडियाकर के बारे में सीखचों के बाहर रहनेवाला एक मीडियाकर कुछ लिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ■

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक

रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोजमर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर व नये रक्त के निर्माण द्वारा पूरे शरीर का पोषण करती **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा बहुमूल्य जड़ी-बूटियों, केसर, मोती आदि द्रव्यों से निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय, आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो पुरुषों को सदैव निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

स्थानीय विक्रेता से लें या
वी.पी. द्वारा मंगवायें।

राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
शाखाएं: दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
राजवैद्य
शीतल प्रसाद एण्ड संस

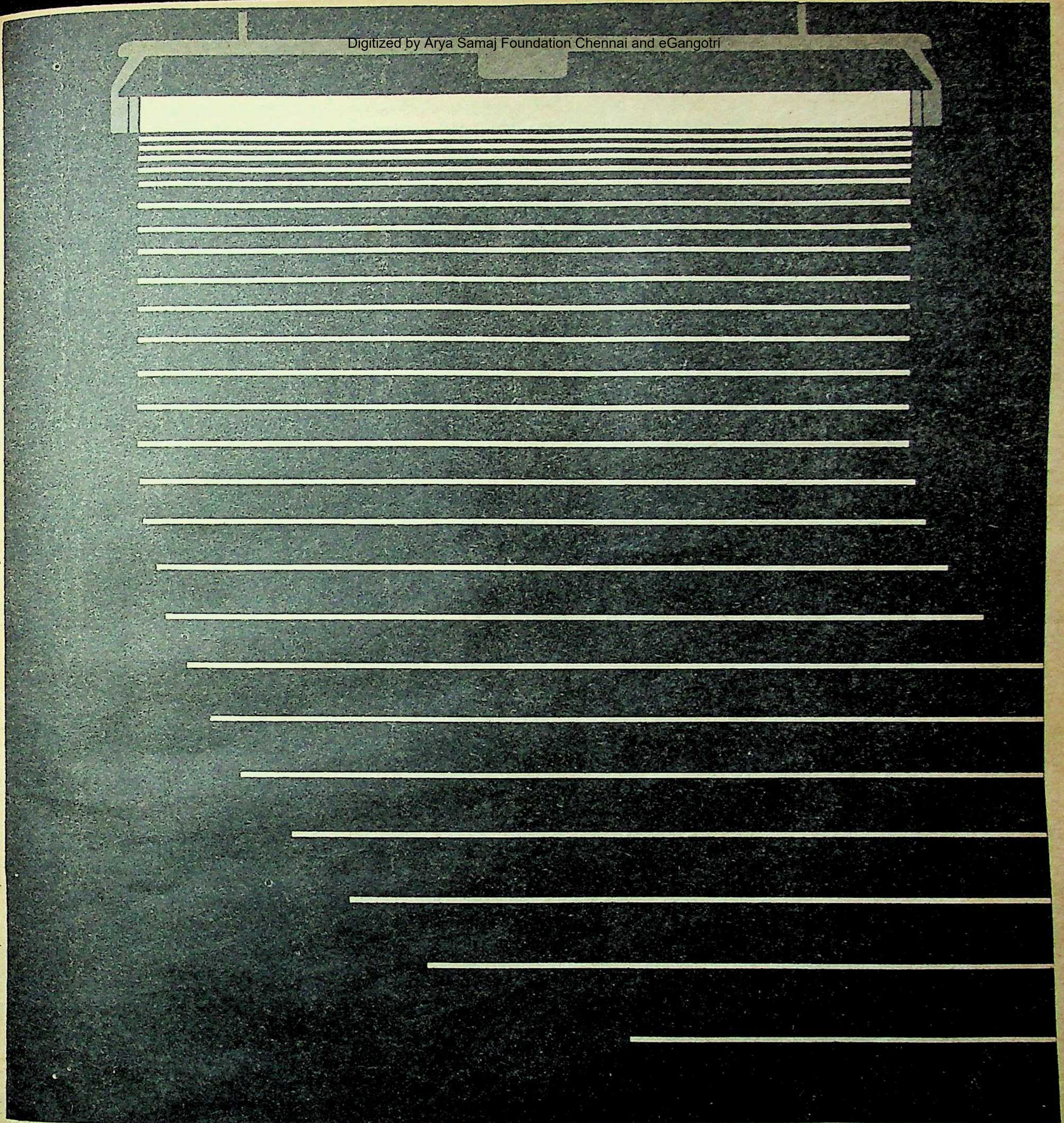

बजाज 'सिल्वरलाइट' पट्टी में किफ़ायती 'बेलास्ट' और सही किस्म का अन्य सामान लगे होने के कारण यह फ़्लोरोसेंट ट्यूब को भरपूर कुशलता से काम करने में सहायता देती है. ताकि आपको बिजली का खर्च कम आए और रोशनी ज़्यादा मिले.

बजाज 'सिल्वरलाइट' पट्टी और बजाज फ़्लोरोसेंट ट्यूब की जोड़ी बेजोड़ है. और किफ़ायती भी. बरसों तक बगैर तकलीफ़ के काम देती है.

bajaj group

बजाज पट्टी और ट्यूब

bajaj

सही रोशनी के लिए सही जोड़ी

Heros/BE-874 HN

आई०एन०एफ० संधि

एक ऐतिहासिक समझौता

रीगन

गोर्बाचोव

लगभग १४ साल बाद किसी रूसी राष्ट्रप्रमुख की अमरीका यात्रा और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को खतम करने के मसविदे पर हस्ताक्षर करना यद्यपि विश्व पर मंडराते परमाणु संकट को खतम करने की गारंटी नहीं है, फिर भी यह ऐतिहासिक अवसर इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं।

लगभग दो साल पहले दोंनों महाशक्तियों के बीच एक लंबे अरसे से चला आ रहा शीत युद्ध उस समय कमजोर पड़ा था, जब सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी 'ग्लासनोस्त' (खुलेपन की नीति) के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए पहल की थी। अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखायी और दोनों तरफ से इस दिशा में काम शुरू हो गया।

नवंबर, १९८५ में रीगन और गोर्बाचोव पहली बार जिनेवा में मिले। इस मुलाकात में हालांकि किसी समझौते की रूपरेखा तैयार नहीं हो सकी, लेकिन बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। अक्तूबर, १९८६ में रेक्जेविक सम्मेलन असफल हो जाने के बाद भी दोनों खेमों ने अपने प्रयास जारी रखे। इसी का परिणाम था कि इसी साल नवंबर के अंतिम सप्ताह में दोनों महाशक्तियों ने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को खतम करने का अंतिम फैसला ले लिया, और इस पर ७ दिसंबर को दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने हस्ताक्षर भी कर दिये।

आई०एन०एफ० (मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों) समझौते के अनुसार ३१० से ३,२०० मील तक मार करने वाले सभी प्रक्षेपास्त्रों को दोनों महाशक्तियां हटा लेंगी। इसके अलावा पश्चिम जर्मनी में तैनात अमरीकी पर्सिंग १-ए-एस प्रक्षेपास्त्र हटा लिये जायेंगे। अमरीका पश्चिमी यूरोप में तैनात २५६ क्रूज प्रक्षेपास्त्र (मारक क्षमता-१,५५० मील), १०८ पर्सिंग-११ प्रक्षेपास्त्र (केवल १० मिनट में, १,१२० मील मार कर सकता है) और ७२ पर्सिंग १-ए. (मारक क्षमता-४५० मील) प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट कर देगा। इन सभी प्रक्षेपास्त्रों का निशाना समाजवादी देश थे। इसके जवाब में सोवियत संघ ४४१ एस०एस०-२० (मारक क्षमता-३,१०० मील), ११२ एस०एस०-४ (मारक क्षमता-१,२४० मील), १३० एस०एस०-१२ (मारक क्षमता-५६० मील) और २० एस०एस०-२३ (मारक क्षमता-३१० मील) प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट कर देगा। दोनों पक्ष इस समझौते का पूरी तरह से पालन करें और नये प्रक्षेपास्त्र (मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाले) न बना पायें इसकी देखरेख की पूरी व्यवस्था इस समझौते में है।

उक्त परमाणु अस्त्र विश्व के कुल परमाणु अस्त्रों के केवल ३ प्रतिशत हैं और बाकी बचे परमाणु अस्त्र विश्व को कई बार खतम करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में यह कदम निश्चय ही उत्साहजनक और स्वागतयोग्य है। इस एक पहल का नतीजा यह निकला है कि अब नाटो (अमरीकी खेमे) और वारसा (रूसी खेमे) संधि के देश पारंपरिक अस्त्रों की कटौती की दिशा में कमर कसते नजर आ रहे हैं। जहां तक दोनों महाशक्तियों के बीच इस दिशा में प्रगति की बात है, तो उन्होंने अगले वर्ष तक लंबी दूरी की मिसाइलों में पचास प्रतिशत की कटौती के समझौते की आशा जतायी है।

कंपूचिया

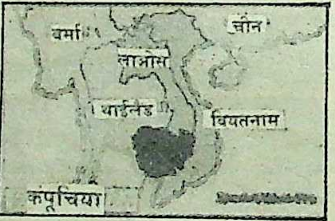

समाधान की ओर

कंपूचिया जनवादी गणतंत्र के प्रधानमंत्री हुन सेन और राजकुमार नरोत्तम सिहानूक की बातचीत के बाद हुए अप्रत्याशित चार सूत्रीय समझौते से इस नौ साल पुराने गृहयुद्ध के समाधान की दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है।

दरअसल, यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा अचानक लचीला रवैया अपना लेने का नतीजा था। अभी तक दोनों पक्ष बातचीत शुरू करने के लिए अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। राजकुमार सिहानूक कंपूचिया की सरकार से बातचीत ही नहीं करना चाहते थे, जबकि वियतनाम खमीर रूजेस (जिन्हें सत्ता से हटा कर वियतनामी सैना ने हुन सेन को गद्दी सौंपी थी) को भाव नहीं दे रही थी।

लगभग नौ साल पहले वियतनाम ने अमरीका समर्थित राजशाही को उलट कर कंपूचिया को जनवादी गणतंत्र घोषित कर दिया था। इस सारी कार्यवाही के बाद भी वियतनामी सेना अभी वहीं बनी है, क्योंकि उसे भय था कि कहीं समाजवादी सरकार फिर न उलट दी जाये। एक अनुमान के अनुसार कंपूचिया में इस समय लगभग एक लाख ४० हजार वियतनामी सैनिक तैनात हैं। उसे सोवियत संघ से भी सहायता मिल रही है। पड़ोसी देश चीन की आंखों में यह सब खटकता है, क्योंकि रूस-वियतनाम दोस्ती से उसे अपनी सुरक्षा का भय सता रहा है। इसीलिए वह कंपूचियाई सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे छापामार दलो को पूरा सहयोग भी दे रहा है।

फ्रांस के फेअर-आं-तार्देन्वा गांव में हुआ यह चार सूत्रीय समझौता बातचीत आगे बढाने के लिए पर्याप्त आधार बनाता है। समझौते के अनुसार-(१) समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढ़ा जाये, (२) शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और तटस्थ कंपूचिया के निर्माण के लिए बातचीत में सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाये, (३) एक शांतिपूर्ण समाधान की खोज के बाद एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाये, जिसकी देखरेख में समझौते को लागू किया जा सके और (४) जनवरी, १९८८ में और उसके बाद किसी तारीख को दोनों पक्ष बातचीत करें।

इस सबके बावजूद मंजिल तक पहुंच पाना तब तक आसान नहीं है, जब तक मास्को और पीकिंग का सकारात्मक सहयोग इस बातचीत को नहीं मिलता। उधर दो लड़ाकू संगठनों (खिऊ सम्फान और सोन सान) को मनाकर बातचीत की मेज पर लाना टेढी खीर साबित हो सका है।

फीजी

नस्लवादी असैनिक शासन की स्थापना

राम्बुका

तमाम विरोधों के बावजूद लगता है ब्रिगेडियर सितिवेनी राम्बुका ने अपनी सैनिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का पहला चरण सफलतापूर्वक निपटा लिया है। ५ दिसंबर को उन्होंने फीजी के भूतपूर्व गवर्नर जनरल रातू सर पिनैया गानिलाऊ को फीजी गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति तथा पूर्व प्रधानमंत्री रातू सर

कामासिसेमारा को पहला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के चार दिन बाद ही प्रधानमंत्री कामासिसेमारा ने अपने २१ सदस्यीय मंत्रिमंडल की घोषणा भी कर दी है।

फीजी मूल के निवासियों का देश की राजनीति में वर्चस्व बनाये रखने के लिए ब्रिगेडियर राम्बुका ने इसी साल २५ सितंबर को एक सैनिक क्रांति के जरिये भारतीय मूल के तत्कालीन प्रधानमंत्री तिमोकी बावंद्रा से सत्ता हथिया ली थी। गत ७ अक्तूबर को उन्होंने फीजी को गणतंत्र घोषित कर दिया था। इसके पहले फीजी का राष्ट्रप्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का प्रतिनिधि हुआ करता था। राष्ट्रमंडल ने एक स्वर से उनकी इस नस्लवादी कार्यवाही का विरोध किया था और फीजी की सदस्यता भी रद्द कर दी थी। इस बीच आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई देशों ने फीजी से अपने आर्थिक संबंध तोड़ लिये, जिससे उसकी अर्थ व्यवस्था भी लड़खड़ा गयी।

नये प्रधानमंत्री कामासिसेमारा एलायंस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो अप्रैल में हुए आम चुनाव में बावंद्रा के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी से हार गयी थी। लेबर पार्टी मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और १९७० में फीजी के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार सत्ता में आयी थी। कामासिसेमारा ने ब्रिगेडियर राम्बुका की सैनिक कार्यवाही का समर्थन किया था, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति गानिलाऊ विरोध करते रहे। गानिलाऊ ने राष्ट्रपति पद भी इसी शर्त पर स्वीकार किया है कि नया प्रस्तावित संविधान स्वीकार होने पर ही वह पद पर बने रहेंगे।

राष्ट्राध्यक्ष का पद त्यागने के बाद ब्रिगेडियर राम्बुका ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि फीजी को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल कर लिया जायेगा। उधर महारानी एलिजाबेथ भी इस परिवर्तन को अपनी सहमति देती नजर आती हैं। लिहाजा, ब्रिटेन-फीजी संबंधों के सुधरने में भी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए।

राष्ट्राध्यक्ष का पद त्यागने के बाद ब्रिगेडियर राम्बुका ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि फीजी को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल कर लिया जायेगा। उधर महारानी एलिजाबेथ भी इस परिवर्तन को अपनी सहमति देती नजर आती हैं। लिहाजा, ब्रिटेन-फीजी संबंधों के सुधरने में भी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए।

कामासिसेमारा मंत्रिमंडल में ज्यादातर लोग उनकी एलायंस पार्टी के हैं तथा उनके पूर्व प्रधानमंत्रित्व काल के मंत्रिमंडल में भी थे। प्रधानमंत्री कामासिसेमारा ने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा है, जिसका उन्हें खासा अनुभव भी है। यह अनुमान भी सही निकला कि गणतंत्र घोषित करने के बाद भी ब्रिगेडियर राम्बुका देश की राजनीति में अपनी पकड़ बनाये रखेंगे। उन्हें गृहमंत्री का भार सौंपा गया है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डा० बावंद्रा को मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया नहीं गया था या वह खुद्र ही शामिल नहीं हुए।

नये मंत्रिमंडल में सैनिक अधिकारियों का वर्चस्व है। राम्बुका के अलावा तीन बड़े सेना अधिकारी शामिल किये गये हैं। भारतीय मूल के केवल दो लोगों को इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है।

—मुकेश कुमार

मनोहर कहानियाँ

जनवरी १९८८

ठगी के जादूगर

नटवरलाल

का पचास साल की ठगी का

दिलचस्प इतिहास

० ठगी करना जिसकी आदत है, शगल है, जिंदगी है

० आधी सदी बीत गयी ठगी करते

० २६ वर्ष देश की विभिन्न जेलों में

० बुद्धि-कौशल से बार-बार फरार

० सन् १९६३ तक ११३ साल की सजा

० मंत्री-मुख्यमंत्री का निजी सचिव, जिलाधिकारी का वेलफेयर आफीसर, परचेज आफीसर, जिला जज का सेक्रेटरी, मिलिट्री ठेकेदार, व्यापारी आदि-आदि बनकर ठगी के बेशुमार कारनामे

० नकली हुंडियों, जाली रेलवे रसीदों और फर्जी बैंक ड्राफ्टों का उस्ताद

० जिसके 'कार्यक्षेत्र' कलकत्ता-मद्रास-बम्बई-दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद आदि-आदि नगर-महानगर रहे हैं

० और अब पुलिस रिकार्ड के अनुसार, ३८वीं बार गिरफ्तार दर्जनों नामधारी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव वल्द रघुनाथ प्रसाद निवासी ग्राम रूइया बंगरा जिला सीवान, बिहार/ उस्तादों के उस्ताद उसी नटवर लाल की संपूर्ण कहानी...ठगी के अनोखे कारनामों, गिरफ्तारी और फरारी के दिलचस्प किस्सों के साथ खोजपूर्ण विस्तृत कथा

साथ ही अन्य रोमांचक सत्यकथायें

१ जनवरी १९८८ तक प्रकाश्य

मूल्य रू० ६/-

फेयरफैक्स जांच आयोग के जाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह

जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आर्थिक अपराधियों को फंसाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संगठन 'फेयरफैक्स' की नियुक्ति की थी, अब वही फेयरफैक्स, जांच आयोग की रिपोर्ट के कारण उनके गले का फंदा बन गया है। क्या वास्तव में वी०पी० सिंह ने किसी षड्यंत्र के तहत फेयरफैक्स की नियुक्ति की थी? वी०पी० सिंह ऐसा क्यों कहते हैं कि जांच आयोग की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है और यह उनको बदनाम करने की साजिश है?

पक्षपात का आरोप :एम०पी० ठक्कर

गले में फेयरफैक्स का फंदा? :वी०पी० सिंह

निष्पक्षता पर शक: एस० नटराजन

"न्याय, जिसकी हम बात करते नहीं थकते, उसे मात्र लागू ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी धारणा भी बननी चाहिए कि वह (न्याय) हुआ है। फिर भी कभी-कभी कुछ न्यायालय अस्थायी स्मृतिलोप का शिकार हो बुद्धिमत्ता के ये शब्द विस्मृत कर बैठते हैं। इसके फलस्वरूप कोई-कोई न्यायालय कभी-कभी ऐसी कार्यविधि अपनाता है जो न्यायपालिका के स्वयं के लिए निर्धारित उच्च मानदंडों पर खरा नहीं उतरता।"

इन दो टूक शब्दों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम०पी० ठक्कर ने मुरादाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को फटकारने में न देर की न संकोच। जिला न्यायाधीश का प्रमुख दोष यह था कि उन्होंने वादी को वकील करने का अवसर नहीं दिया था, यद्यपि प्रतिवादी एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की समुचित सुनवायी किये बिना याचिका खारिज करते हुए एक बना-बनाया फैसला सुना दिया था।

किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के इन्हीं मान्य न्यायाधीशों ने अपने एक सहयोगी न्यायाधीश शिवशंकर नटराजन के साथ जारी की गयी अपनी जांच रिपोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और दो वरिष्ठ अधिकारियों भूरेलाल व विनोद पांडे को कठघरे में खड़ा करते समय इस बात का भी मौका नहीं दिया कि वे अपनी सफायी में कुछ कह सकें।

यद्यपि इन तीनों के विरुद्ध सरकार रूपी एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी था। यही नहीं इनके विरुद्ध लगाये गये गंभीर आरोपों में सरकार का तख्ता पलटने और सी०आई०ए० संबंधित विदेशियों से साठगांठ करना शामिल था। यदि इन आरोपों में लेशमात्र भी सचाई है, तो निःसंदेह तीनों के विरुद्ध वही कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जो किसी देशद्रोही के साथ की जाती है। इसके लिए समुचित कानूनी प्रावधान हैं। फिर भी रिपोर्ट आने के प्रारंभिक हर्षोल्लास के बाद कम-से-कम गंभीर और सौम्य कांग्रेसी सांसद इस समूचे प्रकरण पर पुनर्विचार करने लगे हैं।

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान नवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और जाने-माने वकील एन०के०पी० साल्वे ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा, "आयोग की रिपोर्ट आशा के अनुकूल है।" उनके कहने का तात्पर्य कदाचित यही था कि न्यायाधीशों ने सरकार के आरोपों की पुष्टि की है। साल्वे की प्रसन्नता का एक अन्य कारण यह भी था कि उन्होंने उन नौ सांसदों के उस दल की नुमाइंदगी की थी जिसने आयोग के सामने हलफनामा पेश किया था। इस विषय में सत्ता के गलियारों में बराबर चर्चा रही है कि यह हलफनामा स्वयं प्रधानमंत्री सचिवालय में तैयार हुआ था और इतना गुप्त रखा गया था कि इसकी गंध तक किसी को नहीं लगने दी गयी। जिन सांसदों से इस पर हस्ताक्षर कराये गये, उनको इतना समय भी नहीं दिया गया कि वे इसे पूरी तरह पढ़ पाते।

राय उवाच: कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी इस रिपोर्ट पर सबकी बांछें खिली हुई थीं। शायद इसीलिए गुरु-गंभीर भाषणों से उकता कर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कल्पनाथ राय को अपने 'सरस' उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। राय ने अपने गालीगलौज के चिरपरिचित अंदाज में पहले तो 'राजा' को खूब लताड़ा, फिर सुझाव दिया कि रिपोर्ट को जनता-जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य शीघ्र किया जाये। इसे सर्वसम्मति से स्वीकारा जाना अनपेक्षित नहीं था।

'राजा साहब' की प्रतिक्रिया भी इस विवादग्रस्त रिपोर्ट पर आशानुकूल थी। पूर्व वित्तमंत्री ने आरोप लगाया है कि जिस आयोग ने स्वयं गलत कार्यविधि अपनायी है, उसे मुझ पर आरोप लगाने का क्या नैतिक अधिकार है?

ईमानदारी की सजा: भूरेलाल

प्रतिक्रिया यदि किसी की विपरीत रही है, तो वह है नौकरशाहों की। सरकार के एक आला सचिव ने रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 'माया' से बातचीत के दौरान कहा, "यद्यपि भूरेलाल या विनोद पांडे के पूर्व आचरण के कारण उनकी वर्तमान परेशानियों पर आंसू नहीं बहाये जा रहे हैं (खासकर भूरेलाल के), किंतु पूर्ववित्तमंत्री के द्वारा सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बाद भी उन्हें सूली पर चढ़ाना कतई न्यायसंगत नहीं है।"

हीरो फोबिया: उनका मानना है कि भूरेलाल और विनोद पांडे के विरुद्ध आरोपपत्र जारी किये जा सकते हैं और विभागीय जांच के आदेश दिये जा सकते हैं, किंतु उन्हें बर्खास्त कभी नहीं किया जायेगा। "कारण, एक तो उन्हें सरकार के कच्चे चिट्ठों की जानकारी है, दूसरे बर्खास्त किये जाने पर वे 'हीरो' हो जायेंगे।" राजनीतिक गलियारों में दो अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। एक के अनुसार भूरेलाल और विनोद पांडे के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं। दूसरे यह कि विनोद पांडे ने कैबिनेट सचिव को अपने आचरण की सफायी देने से साफ इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि वित्त सचिव ने भी कोई विशेष कार्रवाई कर पाने में पूर्ण असमर्थता व्यक्त की है। उनके अनुसार आयोग द्वारा धारा '८ बी' के तहत नोटिस न देने के कारण गंभीर धर्मसंकट पैदा हो गया है।

आयोग की जांच के दौरान धारा '८ बी' के अंतर्गत नोटिस न दिया जाना इस रिपोर्ट से संबंधित विवाद का प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को सफायी-जिरह का मौका मिलना कानूनन जरूरी होता है, किंतु आयोग ने ऐसा नहीं किया है। स्वाभाविक है कि आज वही लोग आयोग के अन्याय का नारा बुलन्द कर रहे हैं। यही मुद्दा अंततोगत्वा यह तय करेगा कि रिपोर्ट का असली लाभ किसे मिलता है, राजीव गांधी को या विश्वनाथ प्रताप सिंह को।

सामान्यत: ऐसी जांच आयोगों की रिपोर्ट का कोई अधिक महत्व नहीं होता। जैसा कि जनमोर्चा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जनता शासन में शाह आयोग की कड़ी आलोचना के शिकार विद्याचरण शुक्ल का कहना है, "शाह जांच आयोग के आरोपों से बुरी तरह घिर जाने के बावजूद १९८० में कांग्रेस जबर्दस्त बहुमत से सत्तारूढ़ हुई। फेयरफैक्स रिपोर्ट का परिणाम तो यह सीमा भी लांघ जायेगा। हमारे हाथ तो अगले छह महीनों तक आंदोलन-अभियान चलाने का सुनहरा मौका आ गया है।"

इसके विपरीत कांग्रेस खेमे के अनेक सांसदों और जिम्मेदार नेताओं का मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट का आवश्यकता से अधिक उपयोग विश्वनाथ प्रताप सिंह को बदनाम करने के लिए किया, तो भी बाजी उन्हीं के हाथ लगेगी। जनता की सहानुभूति कांग्रेस के प्रति न होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति हो जायेगी। यदि ऐसा हुआ, तो राजीव के सलाहकारों की विश्वनाथ प्रताप सिंह को देशद्रोही और नसली वाडिया जैसे बड़े उद्योगपतियों से संबंद्ध करने की रणनीति नाकाम हो जायेगी।

इस रिपोर्ट का मौखिक आदेशों के संदर्भ को लेकर सरकारी अधिकारियों पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में सभी अधिकारी मौखिक आदेशों, चाहे वह प्रधानमंत्री के हों या उनके सलाहकारों के, पालन करने में बुरी तरह हिचकिचायेंगे। सरकारी अफसरानों के इसी प्रकार के रवैये का खमियाजा जनता सरकार बखूबी भुगत चुकी है। पूर्व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के विशेष सचिव एन०के० सिंह को जनता शासन के दौरान जिस तरह परेशान किया गया था, उसके फलस्वरूप सरकार को नौकरशाही का कभी भी पूर्ण सहयोग नहीं मिला था।

इसकी पूर्व झलक पूर्व विदेश सचिव ए०पी० वेंकटेश्वरन के सहसा निकाले जाने के बाद से ही मिलने लगी है। नौकरशाहों के रोष और उद्वेग का ही एक नमूना केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री पी० चिदंबरम की पत्नी का प्रधानमंत्री को भेजा गया वह बहुचर्चित पत्र है जिसमें उन्होंने अपने पति के दक्षिण की एक महिला सांसद से अंतरंग संबंधों की शिकायत की है। यद्यपि प्रधानमंत्री के सचिवालय ने सरासर इनकार किया है कि ऐसा कोई पत्र मिला है, किंतु सत्ता के गलियारों में चर्चा इसी बात की है कि यह पत्र खुफिया विभाग के उन अफसरों द्वारा भेजा गया था जो गृहराज्यमंत्री से रुष्ट हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त वेद मरवाह की पुन: नियुक्ति के पीछे भी नौकरशाही के रोष को शांत करने की सरकारी कोशिश बतायी जाती है।

असंतोष के लावे: सरकारी अधिकारियों का बढ़ता असंतोष और रोष अंतत: राजीव सरकार के लिए एक सरदर्द साबित हो सकता है जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी कार्यप्रणाली और नीतियां ही जिम्मेदार ठहरायी जायेंगी। न्यायपालिका में भी असंतोष का लावा खदबदाने लगा है। उसकी चिंता का प्रमुख कारण है न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता। रिपोर्ट को राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताने वाले न्यायविदों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अनुसार, "सरकार ने अपनी झूठी साख बनाने के लिए आयोग के सीमा क्षेत्र में आने वाले विषयों को सीमित करके खुद न्यायालय और न्यायाधीशों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है।" उनके अनुसार बंद कमरे में हुई आयोग की बैठकें, कार्यविधि पहले से तैयार करने में पूर्ण अक्षमता और जांच आयोग कानून के तहत अनिवार्य धारा '८ बी' का पालन न करने का भविष्य में घातक प्रभाव होगा।

गुनाह बेलज्जत: विनोद पांडे

उल्लेखनीय है कि बांबे डाइंग के स्वामी नसली वाडिया के अलावा किसी अन्य को इस धारा के अंतर्गत नोटिस नहीं दी गयी, यद्यपि विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूरेलाल और विनोद पांडे तीनों की ही मान-मर्यादा को धूलधूसरित करने का इस रिपोर्ट में प्रयास किया गया है। यह अलग बात है कि जनता इस पर विश्वास करे या ठुकरा दे।

दूसरी ओर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने रिपोर्ट की पूरी पुष्टि की है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई याचिकादाता अपने पक्ष में निर्णय कराकर खुद ही वाहवाही लूटे। इससे न तो रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ती है, न ही विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि के विरुद्ध लगाये आरोपों को वज़नी बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट में लगे तमाम आरोप विभिन्न कांग्रेसी नेताओं द्वारा पहले से ही संसद के भीतर और बाहर निरंतर लगाये जाते रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण करने वाले कांग्रेस विधायक देवेन्द्र पांडे का तो यहां तक दावा है कि उनके पास वी०पी० सिंह और फेयरफैक्स के माइकल हर्शमैन के बीच हुई गुप्त बातचीत का एक १५ मिनट का टेप भी है। उनका यह भी दावा है कि उनके पास हर्शमैन द्वारा भूरेलाल के जरिए वी०पी० सिंह को १० हजार डालर दिये जाने के पक्के सबूती दस्तावेज हैं। कहने का तात्पर्य है कि आयोग को भलीभांति पता था कि पूरा मामला राजनीतिक है, किसी पूर्व मंत्री की कार्यविधि की जांच का नहीं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह को बदनाम करने की कोशिश उनके केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने के दौरान डइया ट्रस्ट के मामले को उछालकर भी की जा चुकी थी, किंतु सारा मामला टांय-टांय फिस्स हो गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूरेलाल,

साक्षात्कार/गुलाम नबी आजाद, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

सिंह जेल जाने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं

माया: ***कांग्रेस पार्टी और सरकार ने फेयरफैक्स आयोग की रिपोर्ट को किस रूप में लिया है?***

आजाद: इस रिपोर्ट ने उन सभी संदेहों को मिटाया है जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सरकार को थे, बल्कि विपक्ष को भी थे और जिन्हें विपक्ष ने खुलेआम संसद में विचार-विमर्श के बीच जाहिर किया था। सभी को इस बात की आशंका थी कि फेयरफैक्स एक साफ एजेंसी नहीं है और अंततः देश की सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। अब जब हर्शमैन ने स्वयं घोषणा की है कि यदि उनकी रिपोर्ट से भारत अस्थिर होता है, तो उन्हें कोई चिंता नहीं, तब फेयरफैक्स की नियुक्ति और उससे संबंधित सभी व्यक्तियों पर अनेक प्रश्नचिह्न लग गये हैं। मेरी समझ में जब वी०पी० सिंह को यह लगा कि वह इस सिलसिले में फंस रहे हैं और यह मालूम हो जायेगा कि वह भारत विरोधी शक्तियों के साथ हैं, तो उन्होंने पनडुब्बी-बोफोर्स आदि बेबुनियादी मामलों को दूसरों को फंसाने की नीयत से घसीटा और प्रचारित किया।

अगर आपको वी०पी० सिंह और फेयरफैक्स पर संदेह हो गया था, तो आपने वी०पी० सिंह के वित्त मंत्रालय छोड़ने के महीनों बाद तक फेयरफैक्स की नियुक्ति क्यों जारी रखी?

आजाद: जब एक बार संदेहों का खुलासा हो गया, तो उसका काम तो वहीं ठप हो गया। हमारी समझ में यह एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसमें कुछ उद्योगपतियों के इशारे पर वी०पी० सिंह खुद शामिल थे।

माया: यदि रिपोर्ट में आपके सभी दावों, संदेहों की पुष्टि हुई है, तो आपका अगला कदम क्या होगा?

आजाद: इस मामले में वी०पी० सिंह की चुनौती एक राजनीतिक चैलेंज है। वह जानते हैं कि अगर कोई मंत्री गलत निर्णय ले, तो उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। उसको ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद से हटाया जाता है। उस पर केस तो नहीं किया जाता। वी०पी० सिंह ने जो चैलेंज दिया है, उससे वह समझते हैं कि लोगों के जज्बात उभरेंगे और सरकार पर कानूनी कदम उठाने को उकसा कर स्वयं हीरो बन जायेंगे।

माया: जनता-जनार्दन के बीच रिपोर्ट की प्रामाणिकता को आप कैसे स्थापित करेंगे?

आजाद: मेरे ख्याल मे इसमें प्राकृतिक न्याय न कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने यह किया था। उन्होंने कई मर्तबा तोड़मरोड़ कर जवाब दिये हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब पांडे और गुरुमूर्ति ने यह किया, तब उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।

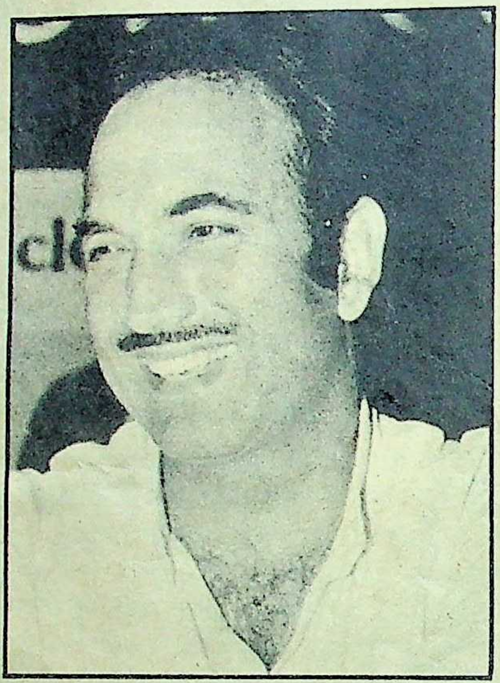

माया: वी०पी० सिंह यह आरोप लगा रहे हैं कि उनमें से किसी को भी '८ बी' के तहत नोटिस नहीं दी गयी जो कानूनन अनिवार्य थी। इससे जनता में यह धारणा बन गयी है कि एक तो कमीशन की रिपोर्ट पक्षपात पूर्ण हो सकती है, दूसरे उसने कानून के मूल मुद्दों को नजरंदाज कर दिया है।

आजाद: इसे पक्षपातपूर्ण कहना ही मानहानि है। यह कोई छोटे स्तर के न्यायाधीशों का आयोग नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय के पदारूढ़ न्यायाधीशों का था। मैं समझता हूं उनका ऐसा कहना बिलकुल उचित नहीं हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कमीशन को चैलेंज नहीं किया है। वी०पी० सिंह तो किसी भी तरह जेल जाने का उपाय सोच रहे हैं। वह समझ रहे थे कि दो चार महीने में हम उन्हें जेल भेज देंगे, पर हमने नहीं भेजा। फिर उन्होंने सोचा कि फेयरफैक्स के मामले में जेल में डालेंगे, पर हम डालने वाले नहीं। इसलिए अब वह मानहानि कर जेल जाना चाहते हैं, जिससे वह किसी तरह हीरो बन जायें।

माया: देश की सुरक्षा को फेयरफैक्स की तैनाती द्वारा किस रूप में खतरा पहुंचा, क्योंकि रिपोर्ट में कोई प्रमाण नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार न तो उन्होंने कोई सूचना दी और न ही कोई अदायगी हुई।

आजाद: रिपोर्ट के अन्दर प्रमाण बराबर हैं। उसके अनुसार—हर्शमैन ने स्वयं स्वीकारा है कि उनके सभी सहयोगी अमरीकी गुप्तचर विभागों में जैसे सी०आई०ए० में काम किये हुए हैं। रिपोर्ट आगे स्पष्ट रूप से कहती है कि फेयरफैक्स जैसी एजेंसी गलत सूचना दे सकती है और स्वयं नियुक्त करने वाले को ब्लैकमेल कर सकती है। हर्शमैन ने स्वयं इसका उदाहरण विभिन्न धमकियों द्वारा पेश किया है।

माया: क्या उन्होंने कोई सूचना दी है?

आजाद: सूचना के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु जिस तरह की धमकियां सिंह का पक्ष लेने के लिए हर्शमैन देता रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसके और वी०पी० सिंह के बीच तालमेल आज भी बना हुआ है। इस रिपोर्ट से दो और चीजें स्पष्ट हुई हैं। एक तो यह कि वी०पी० सिंह की नीयत ठीक नहीं थी। दूसरे वह गोयनका और नसली वाडिया के इशारों पर चलते थे।

माया: नसली वाडिया के खिलाफ तो उन्होंने छापा भी डलवाया था?

आजाद: यह तो दिखावा था। कमीशन ने तो यह भी बताया है कि कब नसली वाडिया मिलता था और कब गुरुमूर्ति मिलकर सलाह करते थे। कमीशन ने यह भी बताया है कि ऐसा लगता था कि प्राइवेट कम्पनी वित्त मंत्रालय को चलाती थी। मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ा इलजाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी मंत्री या मंत्रालय पर नहीं लगाया गया।

माया: यदि वास्तव में फेयरफैक्स द्वारा कोई भी सूचना नहीं मिली है, तो अप्रवासी भारतीयों के अध्यक्ष लतीफ खान ने अमरीकी फेडरल न्यायालय में फेयरफैक्स के खिलाफ यह केस क्यों दायर किया है कि फेयरफैक्स ने उनकी आर्थिक हैसियत और कारोबार का ब्यौरा भारत भेजा।

आजाद: यह तो सरकार को मालूम होगा, मुझे नहीं।

माया: कमीशन ने आर्थिक अपराधों के बुनियादी मुद्दे को जिस ढंग से नजरंदाज किया है, क्या उसका मतलब यह है कि आर्थिक अपराध, विशेषकर देश का पैसा गैरकानूनी ढंग से बाहर ले जाना कोई अपराध नहीं?

आजाद: बिलकुल है अपराध, लेकिन यह काम कमीशन को नहीं सौंपा गया था।

माया: आपके हिसाब से इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? क्योंकि वी०पी० सिंह जनता के समक्ष जाकर अपनी बात रखेंगे, इसका भरपूर उपयोग करेंगे। कहेंगे कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है।

आजाद: वह यदि इसका उपयोग करेंगे, तो हम भी उन्हें नंगा करेंगे। उनके सभी कारनामों को उघाड़ेंगे। जैसा हमने उ०प्र० में किया है। आज तो वह उ०प्र० में घुस नहीं सकते।

—रंजना कक्कड़

वाडिया और हर्शमैन के बीच साठगांठ का माहौल पैदा करने में भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ी गयी। यहां तक कि जाली पत्र भी प्रसारित किये जा चुके थे और एक्सप्रेस समूह के समाचारपत्रों के स्वामी गोयनका के सुंदरनगर स्थित बंग़ले पर छापा भी मारा जा चुका था।

प्रतिक्रियाएं: वर्तमान विस्फोटक राजनीतिक परिदृश्य में यह अत्यंत आवश्यक था कि सिंह आदि को अपनी सफायी देने का मौका दिया जाता। जैसा कि कानूनी स्तंभकार एम०जे० एंटनी का कहना है, "किसी भी जांच आयोग की साख का मूलाधार है जांच के दौरान अपनायी गयी कार्यविधि और रिपोर्ट के प्रति जनता की विश्वसनीयता। न्यायपालिका जनता के विश्वासों का आईना है।"

यह अवश्य सत्य है कि कोई भी आयोग जांच आयोग कानून के समस्त प्रावधानों को मानने और अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी अभी तक अधिकांश आयोगों ने सार्वजनिक जांच और प्राकृतिक न्याय पर बल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच०आर० खन्ना ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री बीजू पटनायक के विरुद्ध जांच आयोग के दौरान ब्रिटेन के प्रख्यात न्यायविद लार्ड स्नो का यह उद्धरण दोहराया था, "न्याय की पहली शर्त है सार्वजनिक सुनवायी। जहां इसकी उपेक्षा होती है वहां समुचित न्याय की आशा नहीं की जा सकती।"

किंतु गत वर्ष जांच आयोग कानून १९५२ के संशोधन के दौरान संसद में हुए विचार-विमर्श में गृहमंत्री बूटा सिंह ने कहा था, "सरकार को निर्देश और परामर्श देना जांच आयोग का प्रमुख कार्य है।" ठक्कर-नटराजन आयोग इस मायने में पूरी तरह खरा उतरा है। सरकार संतुष्ट है, प्रधानमंत्री के सलाहकार तो उससे भी ज्यादा संतुष्ट और प्रसन्न हैं। कांग्रेसियों को जैसे रिपोर्ट से कारूं का खजाना मिल गया है। यदि कोई असंतुष्ट है, तो स्वयं संदेह, विवाद और आरोपों में घिरे विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि, किंतु इन लोगों को भी आयोग ने अपने आधे-अधूरे कामों से एक मनचाहा मौका दे दिया है, जिससे कि वह जनता की अदालत में जाकर रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा सकें और उसके खोखलेपन को उजागर कर सकें।

इनका शोर मचाने का सबसे प्रमुख कारण है—सिंह, लाल और गुरुमूर्ति को धारा '८ बी' के तहत नोटिस नहीं देना। यह नोटिस केवल नसली वाडिया को दी गयी थी, जिन्होंने अपने वकील रामजेठमलानी की सलाह पर आयोग के सामने तब तक पेश होने से इनकार किया जब तक कि आयोग की कार्यविधियां भली-भांति स्पष्ट न की जायें। कुछ जानकार सूत्रों का आरोप है कि राजीव गांधी के निकट के एक पूर्व सांसद की पत्नी ने वाडिया पर काफी जोर डालने का प्रयास किया कि वह 'सत्य' को उजागर करें। तात्पर्य यह कि वह वी०पी० सिंह के सिर यह दोष मढ़ दें कि उनके (वी०पी० सिंह) कहने पर ही वाडिया ने हर्शमैन को अदायगी की।

सूत्रों के अनुसार जब वाडिया ने सहयोग देने से शायद इसलिए इनकार किया कि कहीं वी०पी० सिंह पुनः वापस (सत्ता में) न आ जायें, तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं। ऐसी अनेक अफवाहें फेयरफैक्स कांड के उद्घाटन के बाद जोर-शोर से फैलने लगीं। एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद के अनुसार, "समस्त प्रकरण में नामीगिरामी लोगों की शिरकत को देखते हुए आयोग द्वारा कम-से-कम पूर्व वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सुनवायी और जिरह के लिए बुलाकर यह स्थापित करना बहुत जरूरी था कि क्या सच है और क्या झूठ। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए तरह-तरह की परस्पर विरोधी बातों का फैलना स्वाभाविक है।"

वी०पी० सिंह का कहना है कि अगर आयोग ने उन्हें धारा '८ बी' के अंतर्गत जिरह की अनुमति दी होती, तो वह खुद प्रधानमंत्री को जिरह करने के लिए बुलाकर 'दूध का दूध और पानी का पानी' कर देते। श्री सिंह के इस दावे में कितना दम है, यह तो कहा नहीं जा सकता, किंतु यह अवश्य सत्य है कि आयोग ने उन्हें न बुलाकर वी०पी० सिंह को एक ऐसा घातक हथियार सौंप दिया है जो रिपोर्ट की विश्वसनीयता को चकनाचूर करने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल आयोग की इस चूक के कारण शायद समस्त राजनीतिक परिदृश्य के बदलने का खतरा पैदा हो जायेगा। संभव है कि

कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब
चुटकी पान मसाला खाईए जनाब
सौंफ इलायची छुआरे वाला
चुटकी
पान मसाला
Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"
Chutki
CHUTKI
चुटकी
چٹکی

साक्षात्कार/**विश्वनाथ प्रताप सिंह**

रिपोर्ट अन्याय का एक बेमिसाल दस्तावेज है

माया : क्या पहले से आपको अंदेशा था कि ठक्कर-नटराजन आयोग की कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आयेगी। रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वी०पी० : रिपोर्ट की जांच तो आप केवल इसी एक बात से कर लीजिए कि जो आर्थिक अपराधी थे, जिनके खिलाफ पूरा अभियान वित्त मंत्रालय ने चलाया था, उन्हें इस रिपोर्ट से सबसे अधिक खुशी हुई है। मेहनती-ईमानदार अधिकारियों का मनोबल इस रिपोर्ट से टूटा है। एक तो सीधा प्रभाव रिपोर्ट का यह पड़ा है। दूसरा, किसी भी कानूनी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है। यदि धारा '८ बी' के तहत किसी को नोटिस दी गयी होती-मसलन भूरे लाल, विनोद पांडे अथवा मुझे-तो उस स्थिति में अपने बचाव के लिए आदमी सबूत पेश कर सकता है, वकील कर सकता है, जिरह कर सकता है। कानूनी प्रावधानों का अनुसरण न करके हम समझते हैं कि ठक्कर-नटराजन आयोग ने भविष्य के समस्त जांच आयोगों की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न-चिह्न लगा दिया है।

माया : आपके विचार से आयोग ने किन कारणों से कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया ?

वी०पी० : मैं नहीं जानता। किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुझे बचाव का कोई भी मौका क्यों नहीं दिया ? राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी वकील करने का मौका दिया गया था। इस प्रकार यह रिपोर्ट तो अन्याय का एक बेमिसाल दस्तावेज है। इसके द्वारा भविष्य के लिए सरकार एक ऐसा दरवाजा खोल रही है कि जब किसी से राजनीतिक बदला लेना हो, तो कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाकर एक आयोग बैठा दे। फिर संबंधित व्यक्ति को बचाव का कोई राई-रत्ती मौका न देकर मनचाही रिपोर्ट जारी कर उसे कठघरे में खड़ा कर दे।

माया : इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आप कोई कदम उठायेंगे ?

वी०पी० : ऐसी निराधार रिपोर्ट पर, कानूनी कार्रवाई में हम समय क्यों गंवायें ? मैं तो चुनौती देता हूं, अगर इस रिपोर्ट और सरकार में जरा भी दमखम है, तो हम पर कार्रवाई करे। अगर वह ऐसा नहीं करती, तो इसका मतलब होगा कि न तो इस रिपोर्ट में सचाई है और न ही इस सरकार में कोई कूवत है। जैसे रिपोर्ट खोखली है, वैसे ही सरकार भी खोखली है। मैं सरकार को कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय देता हूं।

माया : हो सकता है, आपके विरुद्ध कोई विशेष कार्रवाई न हो, किन्तु कुछ अधिकारियों, जैसे भूरेलाल, विनोद पांडे—के विरुद्ध तो कदम उठाये जा सकते हैं। उनको इस बात का भी मौका नहीं मिलेगा कि वे प्रेस (जनता) तक अपनी बात पहुंचा सकें।

वी०पी० : हां, सबसे दुखद बात यही है। विनोद पांडे और भूरेलाल ईमानदार अफसर हैं। उन्होंने हर जगह अपनी कर्तव्यनिष्ठा की छाप छोड़ी है। देश के सरगना आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्होंने रात-दिन एक करके सबूत एकत्र किये। इस कठिन काम में उनकी जान को खतरा था। यदि वे चाहते तो लाखों की संपत्ति बना सकते थे। पर असलियत यह है कि भूरेलाल के पास आज एक गाड़ी तक नहीं है। इतनी बड़ी जंग के बीच उन्होंने देश व सरकार के लिए जी-जान से काम किया और उसका यह फल मिला है उन्हें।

माया : प्रश्न यह है कि भूरेलाल का क्या आप साथ देंगे ?

वी०पी० : अवश्य देंगे। हालत यह है कि उनके काम की तारीफ करना तो दरकिनार, उन्हें बचाव का कोई मौका दिये बिना अभियुक्त के रूप में पेश कर दिया गया। इस तरह उन्हें एक अंधेरी-बंद गली में खड़ा कर दिया गया है। इस रिपोर्ट से नौकरशाही का मनोबल बुरी तरह से टूट गया है। एक तरह से यह धन्नासेठों और बड़े पूंजीपतियों की जीत है। यदि मैंने उनका (भूरेलाल) साथ नहीं दिया, तो यह धरती का सबसे बड़ा अनर्थ हो जायेगा।

माया : देश में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप रिपोर्ट में लगाया गया है। क्या यह टिप्पणी जांच आयोग के लिए उचित है ?

वी०पी० : उल्लेखनीय बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री अमरीका गये हैं, तब से अस्थिरता फैलाने की बातें बंद हो गयी हैं। ऐसा लगता है कि वहां भेंट-मुलाकात होते ही देश फिर से स्थिर हो गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान केवल दो ही सप्ताह फेयरफैक्स तैनात रहा, पर प्रधानमंत्री ने तो उस एजेंसी का नाम-काम आदि जानने के बाद भी ४ महीने तक तैनात रखा। क्या वह खुद इसके एक पक्ष (पार्टी) नहीं हैं ? क्यों नहीं ठक्कर-नटराजन साहबान ने उन पर अभियोग लगाया ? यदि प्रधानमंत्री ने उस एजेंसी को जानने के बाद बनाये रखा, तो उसे (एजेंसी की नियुक्ति की) आयोग गलत कैसे कह रहा है ?

माया : किंतु रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि आपने प्रधानमंत्री को इस विषय में अंधेरे में रखा।

वी०पी० : क्या अंधेरे में रखा ? क्या सभी गुप्तचर स्रोतों के विषय में प्रधानमंत्री को बताया गया है ? यदि हमें अवसर मिलता, तो यही तो हम जिरह करते। क्या वी०बी० कुमार जितनी गुप्तचर एजेंसियां नियुक्ति करता है या जो उसके स्रोत हैं, उनकी सूचना वह प्रधानमंत्री को देता है ? यह बात तो मंत्री तक को नहीं बतायी जाती। हम आज तक नहीं जानते कि कूमार ने किन-किन एजेंसियों से सूचना प्राप्त की है। 'रा' क्या अपने गुप्तचर स्रोत बताती है ? और फिर हमें तो सूचना लेनी थी, देनी नहीं थी। इस प्रकार अस्थिरता फैलाने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

माया : सूचना प्राप्त करने के दौरान भी गलत सूचना देकर गुमराह करने का खतरा तो रहता ही है।

वी०पी० : ऐसा नहीं है कि जो सूचना हमें मिलती है, हम उसे मान ही लें। हमारी अपनी खुफिया एजेंसियां हैं जो भली-भांति अध्ययन, जांच-पड़ताल और छंटाई का काम करती हैं। आज भी गलत सूचना देने से कौन रोक सकता है, किंतु हम लोग अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। दिमाग बंद करके थोड़े ही कोई खुफिया एजेंसी काम करती है और अगर ऐसा ही खतरा था, तो प्रधानमंत्री ने ४ महीने तक क्यों बनाये रखा ? फाइल उनकी जानकारी में ११ मार्च को आ गयी थी और उस पर पर्याप्त विचार-विमर्श भी हुआ था। तब इसकी नियुक्ति क्यों रद्द नहीं की गयी ? जब हमने

स्वयं इस प्रश्न को उठाया तब कहीं जाकर महीनों के बाद ही इसकी नियुक्ति रद्द की गयी। मेरे कार्यकाल के दौरान-लगभग एक पखवारे तक फेयरफैक्स नियुक्त रहा, उसके लिए तो हमें फांसी पर चढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री उसको महीनों तक पाले रहे, तो इनको (आयोग) हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्हें नोटिस दें या बुलायें। दूसरी बात यह है कि निजी सुरक्षा में तैनात लोगों के प्रशिक्षण के लिए इटली की एजेंसी से ट्रेनिंग दिलायी गयी है। क्या इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता?

माया: यह आप कैसे कह सकते हैं कि इटली की एजेंसी प्रशिक्षण दे रही है?

वी०पी०: प्रधानमंत्री हमारे सामने इससे इनकार करें, तो जानें। यही मेरे साथ अन्याय हुआ है। यदि हमें '८ बी' के तहत नोटिस मिली होती, तो हम इन सभी बातों का पूरा खुलासा-दूध का दूध पानी का पानी-कर देते। यदि '८ बी' की नोटिस हमारे पास आती, तो जिरह करते। खुफिया निदेशालय के निदेशक से पूछते कि विदेशी सूत्रों से आप सूचना प्राप्त करते हैं या नहीं? निदेशालय के पास गुप्त धन है या नही, जिनका उपयोग वह विदेशी सूत्रों से सूचना प्राप्त करने में लेते हैं?

माया: फेयरफैक्स के विषय में आयोग का कहना है कि सरकार को कोई सूचना नहीं दी गयी और पूरे मामले में उसका काम महज दस्तावेज पहुंचाने वाले डाकिये जैसा था।

वी०पी०: कोई खबर दी नहीं गयी, कोई खबर मिली नहीं, कोई अदायगी की नहीं गयी, फिर भी देश की सुरक्षा को अपार खतरा पहुंचा। वाह क्या कमाल की बात है!

माया: क्या इसका यह कारण है कि अमरीका से कोई रिश्तेदारी अभी तक नहीं हुई है जबकि इटली से रिश्तेदारी है?

वी०पी०: यह तो 'ला' (कानून) की बात नहीं, 'इनला' (ससुराल वालों) की बात है। 'ला' में मोहब्बत नहीं होती 'इनला' में मोहब्बत होती है।

माया: एक अन्य आरोप यह है कि फेयरफैक्स के तैनाती संबंधी कोई लिखित रिकार्ड नहीं और सारे रिकार्ड लगभग एक महीने बाद तब बने, जब आपको 'वित्त' से रक्षा मंत्रालय भेज दिया गया।

वी०पी०: रिकार्ड न 'बाटा' के हैं, न 'किर्लोस्कर' के, न 'ब्रुकबांड' के न 'ओरके' के हैं। इन सब पर पड़े छापों में किसी का भी कोई लिखित रिकार्ड नहीं है। खुफिया नेटवर्क (तंत्र) को जब कोई काम दिया जाता है, तो रिकार्ड कम-से-कम रखा जाता है। खुफिया काम में पहली एहतियात यही बरती जाती है कि लिखित रिकार्ड कम-से-कम हों जिससे वह कार्रवाई के पहले जगजाहिर न हो जायें या उसका कोई गलत उपयोग न हो। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि किसी भी मंत्री का मौखिक आदेश उतना ही वजन रखता है जितना लिखित। मैंने तो स्वयं ठक्कर-नटराजन आयोग को यह सूचित किया था कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अनगिनत मौखिक अनुमति और आदेश मुझे दिये जिनका मैंने पालन किया। अगर '८ बी' की नोटिस मुझे मिली होती, तो इन सब बातों को मैं सिद्ध कर देता। रही बाद में फाइल मंगाकर नोट लिखने की बात, तो विनोद पांडे ने स्वयं आयोग को लिखकर दिया है कि उन्होंने जब फाइल भेजी, तो ब्रह्मदत्त को बताया और ब्रह्मदत्त ने उनसे (विनोद पांडे) बताया कि उनकी रक्षामंत्री से बातचीत हो चुकी है। मैंने ब्रह्मदत्त से अनुरोध किया था कि मैं अपने मौखिक आदेशों को रिकार्ड (लिखित) में परिवर्तित करना चाहता हूं और मंत्री को विश्वास में लेने के बाद ही सचिव ने फाइल भेजी। हमने जो 'नोटिंग' की, उसमें पिछली तारीख नहीं डाली, वही असली तारीख डाली। कोई उसके लिए नयी फाइल थोड़े ही बनायी।

माया: आपको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि बाद में फाइल मंगवाकर उसको रिकार्ड करना पड़ा?

वी०पी०: सवाल नैतिकता का था। अधिकारियों से पूछतांछ की जा रही थी। उनको 'फांसी' पर चढ़ाये जाने का खतरा था। ऐसी सूरत में मैं यह लिखकर कैसे नहीं देता कि वे मेरे आदेशों का ही पालन कर रहे थे।

> मैं तो चुनौती देता हूं, अगर इस रिपोर्ट और सरकार में जरा भी दमखम है, तो हम पर कार्रवाई करे। अगर वह ऐसा नहीं करती, तो इसका मतलब होगा कि न तो इस रिपोर्ट में सचाई है और न ही इस सरकार में कोई कूवत है। जैसे रिपोर्ट खोखली है, वैसे ही सरकार भी खोखली है।

माया: आपका अगला कदम क्या होगा?

वी०पी०: हम अपने पुराने मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। ऐसी रिपोर्ट हमारे मार्ग में कतई बाधक नहीं बनेगी।

माया: क्या यह रिपोर्ट आपकी भावी राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख मुद्दा बनेगी?

वी०पी०: यही एकमात्र मुद्दा नहीं है, किंतु इनकी (आयोग) यह तो जवाबदेही होगी ही कि देश को अपनी करनी के बारे में बतायें कि किस अधिकार से उन्होंने नियमों का मनमाना उल्लंघन किया।

—विजय दत्त, रंजना कक्कड

विश्वनाथ प्रताप सिंह कठघरे में खड़े होने के बजाय स्वयं राजीव गांधी और उनकी सरकार पर आर्थिक अपराधियों और उनसे साठगांठ की तोहमत लगायें।

इसकी शुरुआत सिंह ने गत १२ दिसंबर को नागपुर में हुई विशाल किसान रैली में की। उन्होंने वहां एकत्र विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए राजीव गांधी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "आज छुट्टा घूम रहे देशद्रोही आर्थिक अपराधियों की धरपकड़ के लिए सरकार क्या कर रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आर्थिक अपराधियों के गले में फंदा कसने वालों को तो आज कठघरे में खड़ा किया जा रहा है और उन्हें (आर्थिक अपराधियों को) खुला छोड़ा जा रहा है।"

सांप-छछूंदर की गति: नौकरशाहों की स्थिति भी सांप-छछूंदर जैसी हो गयी है। वह इस घोर संशय की स्थिति में हैं कि यदि १९९० के चुनावों में वी०पी० सिंह के लोग सत्ता में आ गये, तो उनका क्या हश्र होगा जो आज या तो सरकार का उलटा-सीधा हुक्म बजा रहे हैं या तटस्थ हैं। वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने 'माया' से कहा, "राजनीतिज्ञ तो आते-जाते रहते हैं। हमें तो चुनकर आने वाले और साउथ ब्लाक की कुर्सी पर बैठने वाले हरेक की एकनिष्ठ सेवा करनी होती है। हमें भली-भांति पता है कि धन्नासेठों को सरकार के हर कामकाज की पूर्व सूचना होती है। यह भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में लागू है। ऐसे तत्वों को पूर्ण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है।"

उनके अनुसार प्रायः मंत्री सचिवों से ऐसे काम कराते हैं जो पूरी तरह नियम-कानून विरुद्ध न होते हुए भी किसी-न-किसी का हित साधन करते हैं। बाद में धर्मसंकट की स्थिति आने पर बलि का बकरा बनना पड़ता है सचिवों को। अपने कथन की पुष्टि में वह श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की एक घटना का उल्लेख कर बताते हैं कि किस प्रकार फाइलों पर की गयी 'नोटिंग' और सूचना 'लीक' कर दी गयी। सीबीआई इस बात की जांच-पड़ताल कर रही थी कि किस प्रकार रिलायंस प्रतिबंधित सामान संबंधी एक साख पत्र (लेटर आफ क्रेडिट) खोलने में सफल हो गयी थी।

इसकी सूचना रिलायंस के अंबानी और बांबे डाइंग के नसली वाडिया दोनों को थी और दोनों अपनी-अपनी ओर से इस मामले में कोशिश कर रहे थे। फर्क इतना था कि एक जांच रुकवाना चाहता था, तो दूसरा जांच करवाना। इसीलिए ऐसी स्थिति न पैदा होने देने के लिए शायद लिखित की जगह मौखिक आदेश अधिक लाभकर पाये गये हैं। यही कारण था कि किर्लोस्कर, बाटा आदि पर छापों-संबंधी अधिकांश आदेश मौखिक रहे।

अतः फेयरफैक्स एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में कोई भी लिखित आदेश न पाये जाने का आरोप विश्वनाथ प्रताप सिंह की विश्वसनीयता पर शायद ही कोई दाग लगाये। वस्तुतः उनके समर्थकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी गत फरवरी में तभी मिल गयी थी, जब भूरेलाल उनके

पास संबंधित फाइल लेकर गये थे। भूरेलाल ने अपनी अमरीकी यात्रा का पूरा ब्यौरा भी ६ फरवरी को प्रधानमंत्री से हुई अपनी भेंट में दे दिया था।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार बाद में ११ मार्च को उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से बातचीत कर इस मामले में उनकी रजामंदी भी प्राप्त कर ली थी। वित्त राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त ने भी सिंह की इसी कार्रवाई की बाद में संसद में पुष्टि की थी। सरकार और कांग्रेस पार्टी यदि इस रिपोर्ट को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ मुहिम तेज करने का प्रयास करेगी, तो यह सफायी देना भारी पड़ेगा कि उनको इसकी गत फरवरी से जानकारी थी। इसी कारण विपक्ष आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे का भरपूर राजनीतिक लाभ उठाते हुए कह रहा है यदि फेयरफैक्स एजेंसी की तैनाती देशहित के विरुद्ध थी, तो उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के चले जाने के बाद कई महीनों तक तैनात क्यों रखा गया?

इसके लिए जवाबदेह सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी और सरकार होगी, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट में इसका कोई उत्तर ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलता है।

अनुत्तरित सवाल: रिपोर्ट में अन्य कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिये गये हैं। उसमें कहा गया है कि फेयरफैक्स द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। किंतु एक अप्रवासी भारतीय और 'इंडियन रेजिडेंस एसोसिएशन' के अध्यक्ष लतीफ एम० खान ने अमरीका के संघीय जिला न्यायालय, कोलंबिया में फेयरफैक्स के विरुद्ध एक केस दर्ज किया है, जिसमें लतीफ और अन्य ने कहा है, "प्रतिवादी (फेयरफैक्स) ने उनकी वित्तीय हैसियतों के बारे में अमरीकी वित्तीय विभाग से प्राप्त गोपनीय सूचना की जानकारी भारत के वित्त मंत्रालय को दी है।" लतीफ आदि ने इस सूचना को लौटाने की मांग की है।

दरअसल 'द स्टेट्समैन' के अमरीकी संवाददाता वारेन ऊना के अनुसार भूरेलाल ने अमरीकी वित्तीय विभाग में फौजदारी मामलों के पदाधिकारी जोजफ ब्रवो को न्यूयार्क के कुख्यात घोटालेबाज जे०के० दोषी और बल्लारपुर ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के विदेशी धंधों, कैलिफोर्निया के सलीम, रिलायंस और ड्यूपाट और कैक्टेक्स के संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दो पत्र लिखे। यह सब सिद्ध करता है कि कुछ सूचनाएं फेयरफैक्स एजेंसी के द्वारा प्राप्त की गयी थीं और उनका संबंध मात्र रिलायंस से नहीं था। जैसा कि जनमोर्चा के एक प्रवक्ता ने सवाल उठाया है, "रिलायंस के खिलाफ जांच क्यों नहीं की जा सकती और उसके बारे में जांच से किस प्रकार सरकार का तख्ता पलट हो सकता है या देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है?"

यदि फेयरफैक्स एजेंसी की तैनाती देशहित के विरुद्ध थी, तो उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के चले जाने के बाद कई महीनों तक तैनात क्यों रखा गया?

सरकार के एक सचिव यह बात स्वीकार करते हैं कि ऐसे आर्थिक अपराधों की जांच, जिसका रक्षा सामानों से संबंध न हो, देश की सुरक्षा के लिए कतई खतरनाक साबित नहीं होती। वैसे भी केवल इस रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक आक्रमण की मुद्रा तो अपनायी जा सकती है, मगर अगले चुनाव, जो राजीव गांधी के अनुसार १९८९ में होंगे, तक इस अभियान को घसीटा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी इससे फौरी लाभ या तो दिल्ली के स्थानीय चुनावों या संसदीय उपचुनाव में उठा सकती है, या वह विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ एक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकती है। किंतु इसके लिए चुनाव पूर्व जनअभियान के अतिरिक्त कुछ कानूनी कार्रवाई भी लाजिमी होगी और यह एक जोखिम भरा कदम होगा।

कहा जाता है कि विनोद पांडे के इस्तीफा देने के विचार को उनके सहयोगियों ने यह कहकर फिलहाल अमल में लाने से मना कर दिया है कि अभी यह देखना फायदेमंद होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा? यदि भूरेलाल इस्तीफा देते हैं, तो उन्हें इलाहाबाद के संसदीय उपचुनाव का उम्मीदवार बनने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करने और बेनकाब करने का सुनहरा मौका मिल जायेगा। कांग्रेस पार्टी फिलहाल इसे झेल पाने की स्थिति में नहीं है।

भूरेलाल के बारे में दूसरी संभावना यह आंकी गयी है कि यदि उन्हें अधिक प्रताड़ित किया गया, तो वह न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। इससे सरकार और जांच आयोग दोनों के खिलाफ जनता के बीच उछल रहे आरोपों को वजनी बनाने में मदद मिलेगी।

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहले ही सरकार को चुनौती दी है कि यदि उसमें दम है, तो वह उनके खिलाफ एक महीने के भीतर मुकदमा चलाये। फिलहाल इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वी०पी० सिंह को 'हीरो' बनने और प्रधानमंत्री को उलटे कठघरे में खड़ा होने का कोई मौका नहीं देना चाहती।

ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है त्यों-त्यों कांग्रेसजनों का प्रारंभिक हर्षोल्लास मद्धिम पड़ता जा रहा है। जैसा कि एक विपक्षी नेता का 'माया' से कहना है, "यह रिपोर्ट अंततः कागजी शेर साबित होगी या वफादार कांग्रेसियों के कमरे की शोभा बढ़ायेगी।"

कागजी शेर जनता पर शायद ही कोई प्रभाव डालते हैं। जैसा कि सरकारिया आयोग का कथन है, "जनता-जनार्दन ही अंततः वास्तविक न्यायाधीश होती है।" दरअसल निकट भविष्य में कांग्रेस के लिए यह जरूरी होगा कि वह इस कागजी शेर में प्राण संचार का सुअवसर विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों को न दे। — विजय दत्त

विनोद पांडे और भूरेलाल पर अभियोग

० एक निजी जासूसी एजेंसी की सेवाएं लिये जाने के निर्णय के बारे में उन्होंने कुछ रिकार्ड नहीं रखा।

० जासूसी एजेंसी फेयरफैक्स के बारे में कोई पूछताछ करने का प्रयास नहीं किया।

० भूरेलाल ने अमरीका जाने का उद्देश्य विस्तार से नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वह रिलायंस व अन्य कंपनियों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करने जा रहे हैं। विभाग किस प्रकार चलाया जा रहा था, यह इसी से पता चलता है कि पांडे के अधीन काम करने वाले अफसर ने बिना किसी बातचीत के उक्त एजेंसी को नियुक्त कर लिया।

० भूरेलाल व पांडे के मध्य, इतने जरूरी मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई।

० पांडे की अमरीका यात्रा के विषय में पांडे व भूरेलाल ने जो बयान दिये हैं, वे आपस में मेल नहीं खाते।

० पांडे ने अपने विभाग की फाइलें वी०पी० सिंह को तब भेजीं जब वह वित्तमंत्री न रहकर रक्षा मंत्री हो गये थें। इस प्रकार फाइले दो दिन तक वित्त विभाग से बाहर रहीं।

० पांडे ने एक निजी विदेशी एजेंसी के चयन व उसकी नियुक्ति की शर्तों में बहुत कम दिलचस्पी ली। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सब कुछ भूरेलाल पर छोड़ दिया था।

० वित्त राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त द्वारा १७ फरवरी को उठाये गये मुद्दों का ९ मार्च तक कोई ज़वाब नहीं दिया गया। पांडे ने इस मामले पर कुछ नहीं किया।

० अमरीकी एजेंसी फेयरफैक्स की सेवाएं लेते समय भूरेलाल ने गोपनीयता से काम लिया।

नसली वाडिया पर अभियोग:

० वाडिया, जिनकी रिलायंस उद्योग समूह के धीरूभाई अंबानी से प्रतिस्पर्धा सर्वविदित है, ने फेयरफैक्स को नियुक्त करने में मदद दी।

० वाडिया ने अपनी कार्यसिद्धि के लिए वित्त मंत्रालय व भूरेलाल का उपयोग किया।

० आयोग के मुताबिक एक प्रकार का मौखिक समझौता हुआ होगा, जिसकी प्रमाण के अभाव में साबित नहीं किया जा सका। ■

MGD S P 88 2721

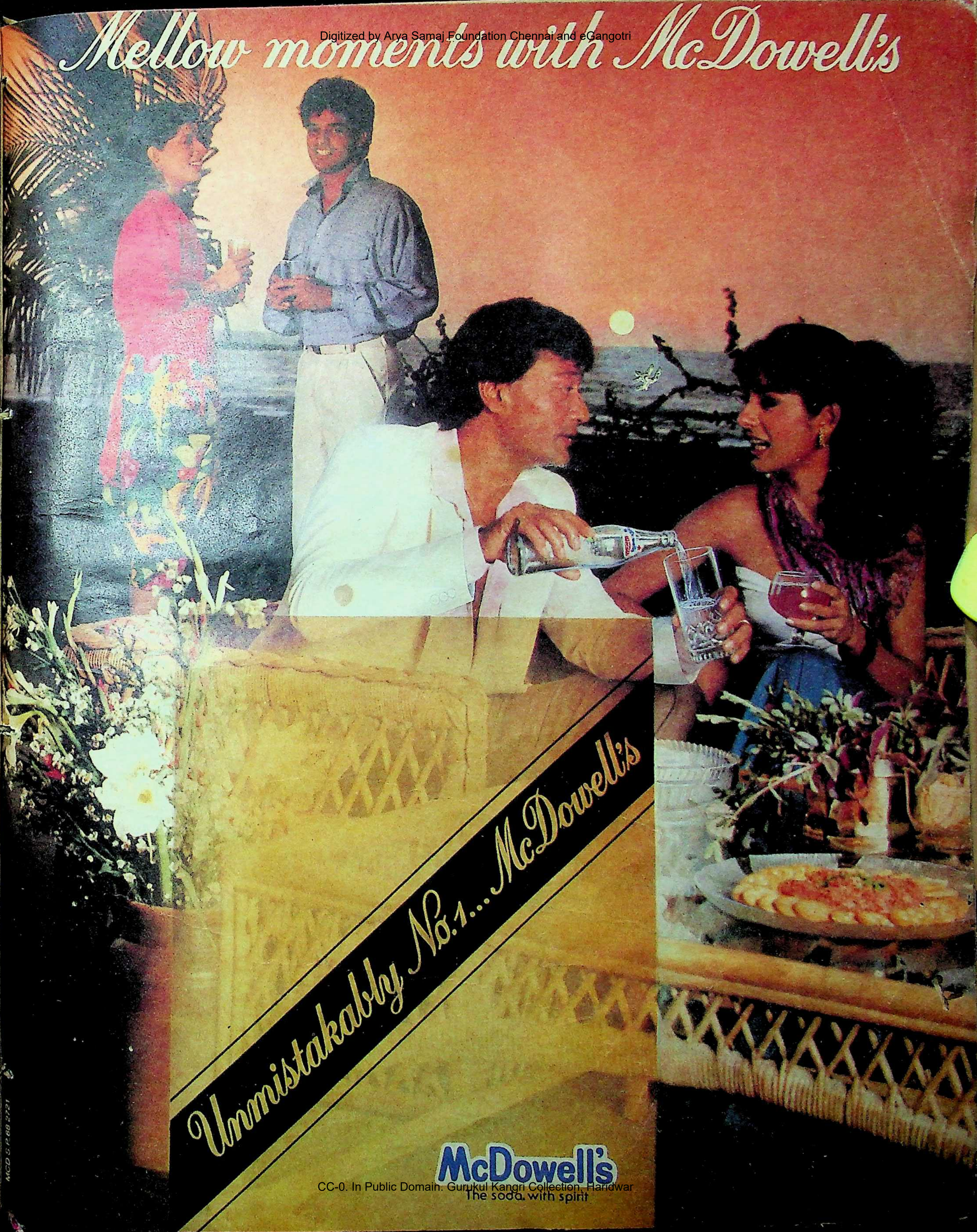
Mellow moments with McDowell's
Unmistakably No.1... McDowell's
McDowell's
The soda with spirit
MCD S.P.68.2721

आशा सचदेव की खुशफहमी

"देखिए, न तो मैं कभी टी॰वी॰ स्टार थी, न हूं और न ही टी॰वी॰ स्टार बनना चाहूंगी। मैं सिर्फ फिल्म ऐक्ट्रेस हूं और आप लोग मुझे डिमोट करने कर क्यों तुले हुए हैं? भला, सिर्फ इसलिए कि दोस्ती के नाते मैंने रमेश सिप्पी का सीरियल (बुनियाद) कर लिया था...मुझे टी॰वी॰ से कोई लगाव नहीं है।" बड़े परदे की ग्लैमर हीरोइन रह चुकी आशा सचदेव छोटे परदे की हीरोइन बनने की बात पर भड़क उठती है। सीरियलों में काम कर रही जानी-मानी हीरोइनों (शर्मिला ठाकुर, मुनमुन सेन, तनूजा, सुप्रिया पाठक आदि) का नाम लिये बिना यह कहने से बाज भी नहीं आती कि,

आशा सचदेव छाया: डी॰आर॰ यादव

"हो सकता है उन बेचारियों की कोई मजबूरी रही हो, उनके पास काम न रहा हो, इसलिए उन्हें सीरियलों का सहारा लेना पड़ रहा हो...।"

यों आशा को आप जब भी फोन कीजिए, एक रटा-रटाया जवाब हाजिर रहेगा, "मेम' साब काम से बाहर गयी हैं" या "अभी बहुत बिजी हैं, अगले सप्ताह फोन करना..., " लेकिन आशा कर क्या रही है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। रोजाना जो फिल्में एनाउंस होती हैं, उनमें आशा का कहीं नाम नहीं होता, फिल्म निर्माता जो प्रपोजल बनाते हैं, उसमें भी आशा का नाम कभी शामिल नहीं होता। यहां तक कि तथाकथित दोस्त रमेश सिप्पी भी अपनी दो-दो फिल्में एनाउंस करते समय कास्टिंग में उनका नाम शामिल करना भूल गये। बुनियाद के दौरान आशा ने ग्लैमरस पोज में एक-से-एक धांसू फोटो खिचवाये भी, छपवाये भी, लेकिन मुसीबत का मारा एक भी फिल्म निर्माता उसके घर की ओर नहीं फटका। उनसे अच्छी तो पद्मिनी कपिला रही जिसने प्रकाश मेहरा का दामन थाम कर बिना विवाह के ही मंगलसूत्र पहन लिया और फिल्म निर्माता बन बैठी, लेकिन बेचारी आशा न इधर की रही, न उधर की। ऐसे में वह अगर अतिव्यस्त होने की खुशफहमी पाल बैठे, तो बुरा क्या?

सोनम का पैंतरा

'रिडल्स आफ फिल्मडम' कहलानेवाली सोनम सचमुच बाक्स आफिस की पहेली बन गयी है। उसकी एक भी फिल्म पूरी, क्या चौथाई भी नहीं बनी है, लेकिन हर सप्ताह उसकी 'प्राइस' बढ़ जाती है और हर मंगलवार को वह बढ़ी हुई 'प्राइस' के साथ कई फिल्में साइन कर लेती है, वह सिर्फ मंगलवार को ही नयी फिल्में साइन करती है, क्योंकि वह गणेश की भी भक्त है और हनुमान की भी।

चंकी पांडे जैसे नौसिखियों से लेकर नाना की उम्रवाले देवआनद के साथ हीरोइन का किरदार निभा रही वही सोनम 'बाबा कहि-कहि जाय' दादा राजकपूर को नहीं भरमा सकी और 'हिना' फिल्म से हाथ धो बैठी, जबकि वह 'हिना' के लिए 'कैसे' भी दृश्य देने के लिए तैयार थी। सोनम, जो अभी कुछ महीने पहले ऋषि से दोस्ती का दम भरा करती थी, अब उससे इतनी खफा है कि उसे देखते ही मुंह फेर लेती है और पास खड़े जूनियर आर्टिस्ट से रस ले-ले कर बतियाने लगती है। कभी-कभी सरे आम उन्हें 'हलो अंकल' कह कर चिढ़ा भी बैठती है। 'अंकल' सुनते ही लाल-पीले होते ऋषि की तरफ से मुंह फेर कर लोगों को सुनाती है, "अब राज साहब को दादा कहूंगी, तो इनको फिर क्या कहूं—अंकल ही न!"

'ब्वाय फ्रेंड' को 'अकल' कह कर लाल-पीला कर देनेवाली सोनम की नाराजगी का कारण 'हिना' का हाथ से निकल जाना नहीं, बल्कि मीनाक्षी शेषाद्री है। इधर ऋषि कपूर जब से मीनाक्षी को जरा ज्यादा भाव देने लगा है और फिल्म निर्माताओं को उसे साइन करने की सलाह देने लगा है, तब से सोनम लाल-पीली हो गयी है। अब सोनम की इस सीधी-सादी पहेली को ऋषि कपूर न समझ पाये, तो भला सोनम का क्या दोष?

छाया: दुर्गा प्रसाद

ऋषि, मीनाक्षी, सोनम

उपासना खोसला की गयी उपासना !

अपने ऊपर लगे ग्लैमर के ठप्पे को दूर कर सच्ची अभिनेत्री की इमेज बनाने के लिए संघर्ष करते-करते शशिकला, हेलन, बिंदू, सायरा बानो आउट हो गयी, लेकिन ग्लैमर के ठप्पे का दाग कुछ इतना गहरा था कि आज भी वह उन्हें मसोसता है, लेकिन उपासना खोसला के साथ कुछ उलटा ही हुआ। मनोज कुमार ने उसे पहले अपने बरखुरदार कुणाल गोस्वामी के साथ लिया, फिर न जाने क्यों उसे हटाकर मीनाक्षी शेषाद्री को ले लिया। दुखी उपासना के शाप ने अपना जलवा दिखलाया—न तो मनोज कुमार की फिल्म चली, न ही उनके बरखुरदार चल पाये, चली तो केवल हीरोइन मीनाक्षी।

मनोज के व्यवहार से संतप्त उपासना ने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को अलविदा कहने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गयी, जब राजश्री वालों ने उसे फिल्म 'बाबुल' की हीरोइन चुन लिया। लेकिन बाक्स आफिस पर 'बाबुल' का सितारा जितनी तेजी से चमका, उससे भी तेजी से उपासना का सितारा अस्त हो गया। सिल्वर और गोल्डेन जुबली मनानेवाली 'बाबुल' की हीरोइन इसलिए बेकार हो गयी कि फिल्म इंडस्ट्री में 'ग्लैमर गर्लों' की भीड़ जुट आयी थी जिन्होने शरीर पर कितना वस्त्र रखा जाये, इसकी जिम्मेदारी निर्देशकों पर डाल दी थी। ऐसी सोन मछलियों की भीड़ में सीधी-सादी लड़की की इमेजवाली उपासना का भला क्या काम ?

सो वही उपासना 'बाबुल' की इमेज तोड़ने के लिए हाटेस्ट फिल्म 'वासना की आग' की हाटेस्ट हीरोइन बन गयी और ग्लैमर गर्लों के लिए खासी मुसीबत पैदा कर दी और ग्लैमर तथा सेक्स की जंग की सारी बाजियां हथिया ले गयी।

उपासना खोसला छाया : जीतेंद्र आर्य

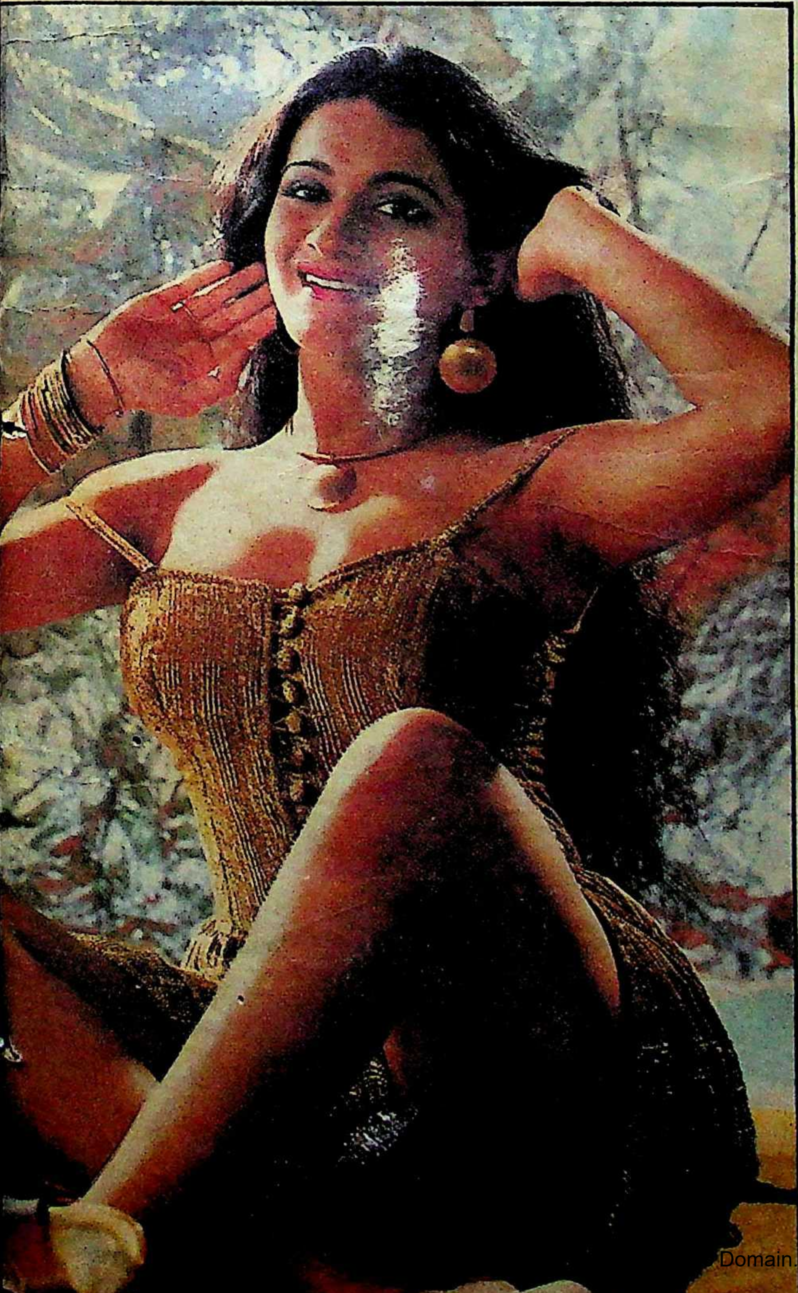

किमी कातकर एवं गोविंदा छाया : डी०आर० यादव

किमी कातकर का बोधिसत्व

इधर किमी कातकर को एक नया रोग लग गया था—अपने अंग-अंग को प्रदर्शित कर चुकने के बाद उसे 'बोधिसत्व' प्राप्त हुआ कि जब यह काया ही नश्वर है, तो इसके प्रदर्शन से क्या फायदा ? सो फोटो सेशन करने आने वाले छायाकारों को वह यही उपदेश देने लगी और नख-शिख ढंक कर चित्र खिचवाने लगी। यह बोधिसत्व कुछ इस कदर बढ़ा कि वह यही 'ज्ञान' फिल्म निर्माताओं को भी देने लगी। लो-कट तथा अंग-प्रदर्शक परिधानों के पहनने की नश्वरता पर उसने ड्रेस डिजाइनरों को उपदेश देना शुरू कर दिया और तैयार सेट पर इन परिधानों के बजाय सांगोपांग ड्रेस पहन कर शाट देने के लिए दबाव डालने लगी। उसका 'आत्म ज्ञान' कुछ इस कदर बढ़ा कि ऐसे रिवीलिंग परिधानों वाले दृश्यों की शूटिंग रुकने लगी और एक-एक कर प्रेस छायाकारों से लेकर फिल्म निर्माता तक उसके दर से लौटने लगे।

पानी सिर से कुछ अधिक हद तक गुजर जाये कि उसके पूर्व किमी की तंद्रा टूटी जब उसने अपने अनुबंधों की फाइल देखी। आधे से अधिक फिल्मों का नाम सूची से कट गया था और इन फिल्मों के निर्माताओं ने 'और भी रिवीलिंग' ड्रेस पहनने के लिए तैयार जूही चावला से लेकर सोनम तक को उसकी जगह साइन कर लिया था। फिर किमी कातकर का 'बोधिसत्व भ्रम' बड़ी जल्दी टूट गया और यह भ्रम तोडनेवाले थे उसके कई फिल्मों में नायक गोविदा और खुद किमी की मां मामा कातकर ! अब यह दूसरी बात है कि सफलता के अहं ने इन दोनों को भी कुछ इस कदर भरमा दिया था कि वे आसमान में कुलांचे भरने लगे थे। मामा कातकर को लगा कि अब किमी श्रीदेवी के टक्कर की हीरोइन बन गयी है, इसलिए वह फिल्म निर्माताओं को सुमीत सहगल, गोविंदा, संजय दत्त के बजाय अमिताभ, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सुपर स्टारों के साथ साइन करने का हुक्म फरमाने लगीं। अब यह दूसरी बात है कि जिस गोविंदा के साथ फिल्में करने के लिए मामा कातकर ने मना कर दिया था, वही उनकी बेटी की मदद के लिए आगे आया।

—अखबारी लाल

Rajnigandha
FLAVOURED PAN MASALA
ताज़गी के पल...
...एक पल में ताज़गी
FUSION/RAJ/10
Rajnigandha
FLAVOURED PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
Rajnigandha
FLAVOURED PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
रजनीगन्धा
पान मसाला
तुलसी ज़र्दा घराने की अनुपम भेंट

कार्टून

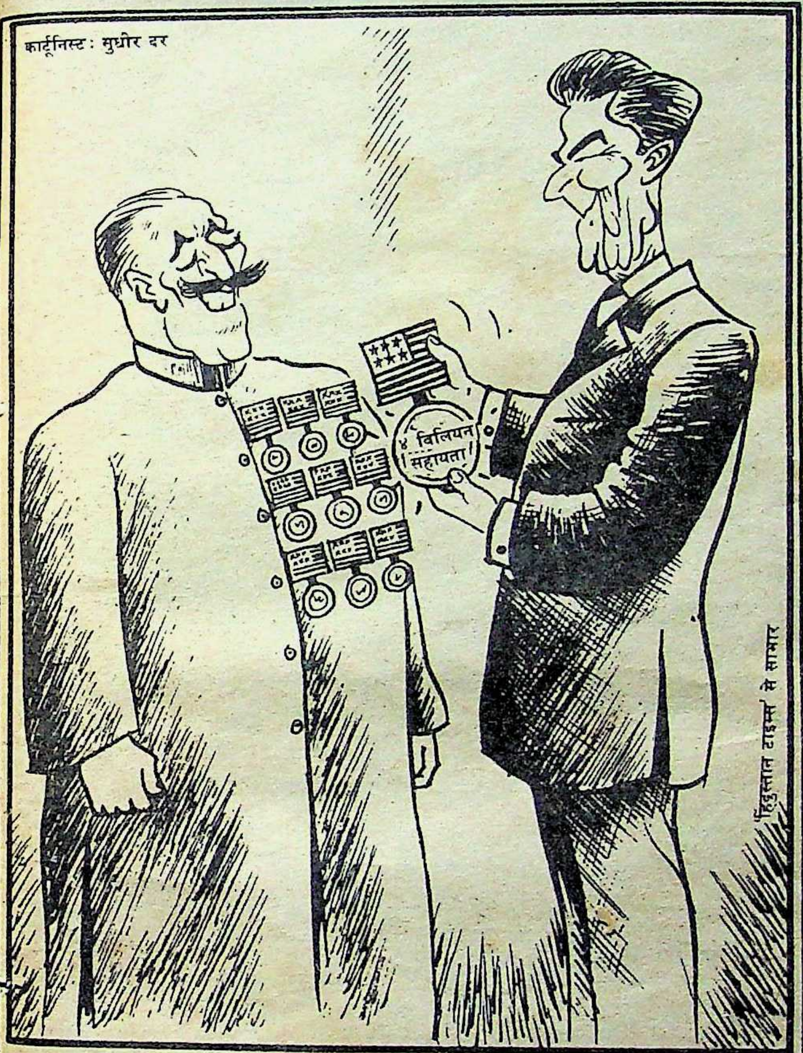
कार्टूनिस्ट: सुधीर दर
'हिंदुस्तान टाइम्स' से साभार

सराहनीय सेवाओं के लिए

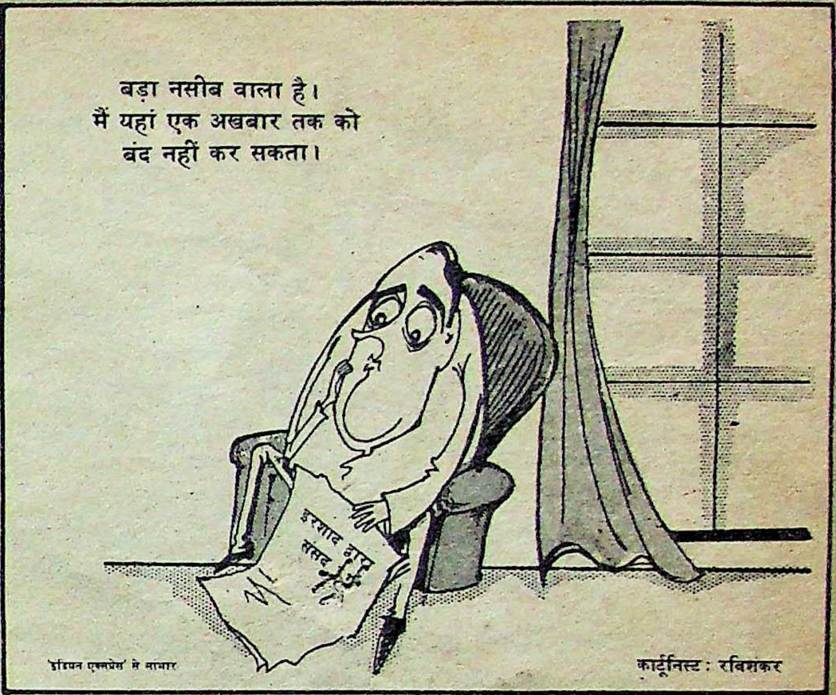
बड़ा नसीब वाला है।
मैं यहां एक अखबार तक को
बंद नहीं कर सकता।
इरशाद
संसद
'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार
कार्टूनिस्ट: रविशंकर

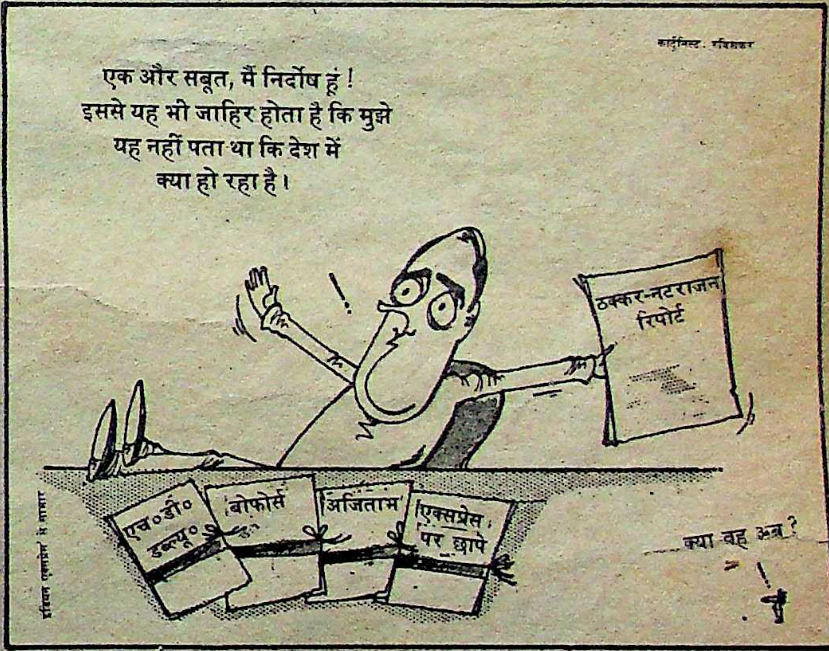
कार्टूनिस्ट: रविशंकर
एक और सबूत, मैं निर्दोष हूं !
इससे यह भी जाहिर होता है कि मुझे
यह नहीं पता था कि देश में
क्या हो रहा है।
ठक्कर-नटराजन
रिपोर्ट
एच०डी०
डब्ल्यू०
बोफोर्स
अजिताभ
एक्सप्रेस
पर छापे
क्या वह अब ?
'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार

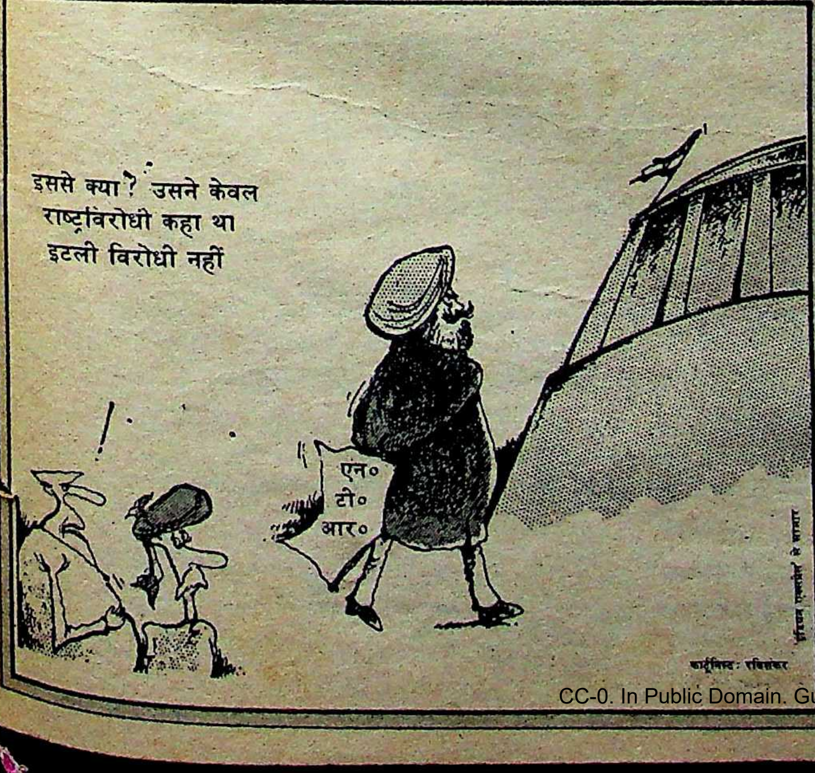
इससे क्या? उसने केवल
राष्ट्रविरोधी कहा था
इटली विरोधी नहीं
एन०
टी०
आर०
'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार
कार्टूनिस्ट: रविशंकर

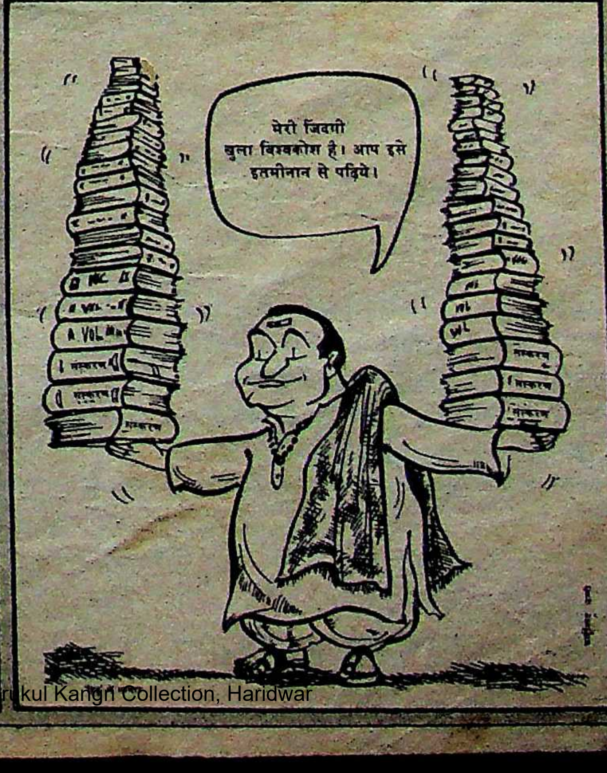
मेरी जिंदगी
खुला विश्वकोश है। आप इसे
इतमीनान से पढ़िये।

नेशनल इंश्योरेंस की फाइल से

एक फैसला, सही समय का...

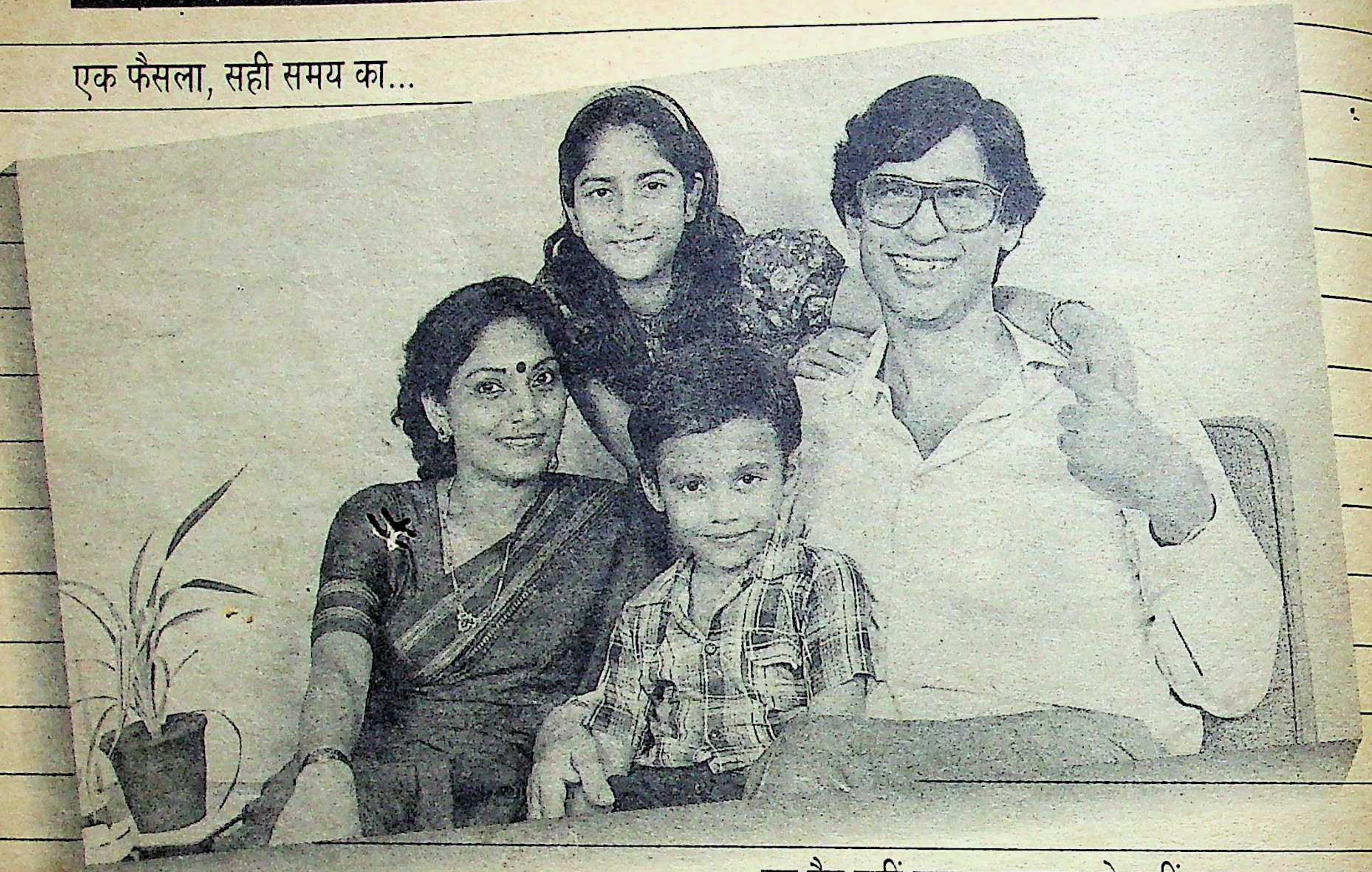

अनिल भार्गव, उम्र ४० वर्ष,
माया के पति, रंजू और मीनू के पिता,
स्नेहशील जीविकोपार्जक,
परिवार का एकमात्र सहारा,
झपट कर चलने वाला, एक बार में
दो दो सीढ़ियां चढ़ते हैं,
चलती बसों पर सवार होने में माहिर,
पिछले सप्ताह, पहली बार, बस के फुटबोर्ड
पर पैर नहीं पड़ा। घायल तो नहीं हुए
लेकिन उनके अहंभाव पर बड़ी चोट लगी।
इस सप्ताह उन्होंने अपने जीवन में
महत्वपूर्ण फैसला किया।
वे नेशनल इंश्योरेंस में गये।
अनिल भार्गव अच्छी तरह समझ गये कि
उनके और उनके परिवार को
नेशनल इंश्योरेंस हाउस होल्डर्स पॉलिसी*
की बीमा-सुरक्षा की आवश्यकता है।

---

* हमारी नई हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिये आग और दंगा-फसाद, हड़ताल या दुर्भावनापूर्ण कार्य, आंधी, तूफान, बाढ़ और जलप्लावन, सेंधमारी, गृहवेध, चौर्य या चोरी जैसे संकटों के कारण घरेलू सामानों की होने वाली क्षति या हानि से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा, बीमा करानेवाला व्यक्ति, कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपनी पसन्द के अन्य दम जोखिमों से भी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ये बीमा सुरक्षा हैं: ऑल रिस्क्स, प्लेट-ग्लास, घरेलू उपकरणों की खराबी, टी.वी. सेट, पेड्ल साइकिल, अस्पताल में भर्ती तथा सरकारी देयता और साथ ही सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, चौर्य या चोरी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे किसी भी कार्यालय से सम्पर्क कीजिए।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन एक प्रतिष्ठान)
सेवा है हमारा प्राथमिक कर्तव्य

CLARION C-NIC-21

भोजपुरी फिल्में

अस्मिता का संकट

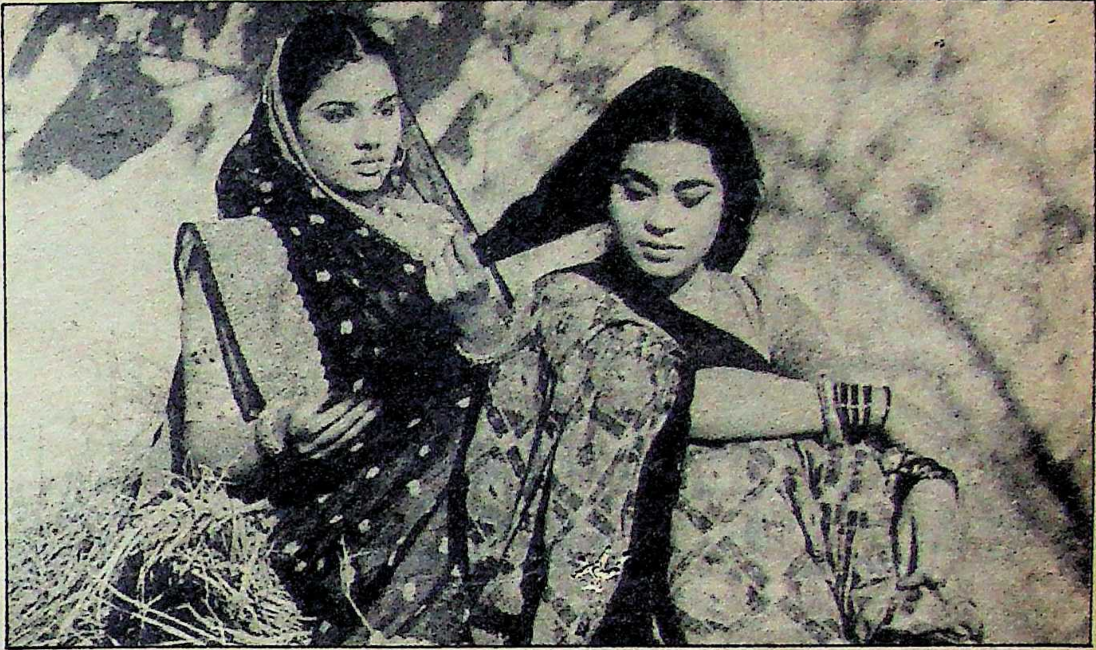

इतिहास स्तंभ : पहली भोजपुरी फिल्म 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो' में पद्मा खन्ना और कुमकुम

रंगीन इतिहास : भोजपुरी की प्रथम रंगीन फिल्म 'दंगल' में सुजीत कुमार और प्रेमा नारायण

भारत में १५ करोड़ से अधिक लोग जिस बोली को बोलते हों, असम से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक फैले हों, सूरीनाम, फिजी तथा मारीशस आदि देशों में जो वहां की एक प्रमुख भाषा के रूप में व्यवहृत हो, वह भोजपुरी अपनी समस्त सांस्कृतिक-पारंपरिक विरासत के बावजूद तिरस्कृत रूप में दबी पड़ी है, लेकिन इससे भी खराब हालत है भोजपुरी में बननेवाली फिल्मों की जो 'सी' क्लास की लक्ष्मण रेखा को २५ वर्षों के भीतर आज तक लांघ नहीं पायी हैं। किसी भी भाषा या बोली की फिल्मों के निर्माण-इतिहास में सिर्फ भोजपुरी के साथ एक गौरवशाली अतीत जुड़ा है कि भोजपुरी की पहली ही फिल्म ने व्यावसायिक सफलता के सारे कीर्तिमानों को तोड़ कर भोजपुरी फिल्म को ऐसी दुधारू गाय बना दिया था, जिसे दुहने के लिए हर कोई पांत लगा कर खड़ा हो गया था। प्रस्तुत है, भोजपुरी फिल्मों के रजत जयंती वर्ष में इसके सभी पहलुओं का लेखा-जोखा : →

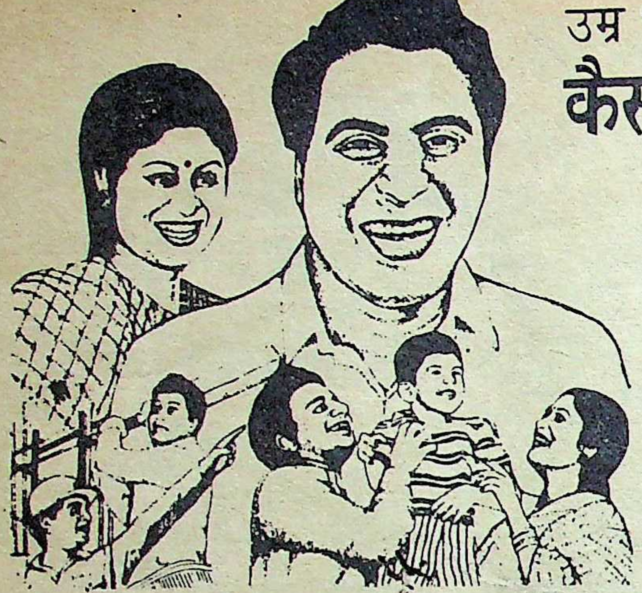

उम्र भी कुछ कम नहीं, फिर भी

कैसा तन्दुरुस्त, कैसा फुर्तीला

ये सब है **ओकासा** की बदौलत
शक्ति के साथ-साथ
काम की लगन भी.

एक अनोखा ज़ोरदार फार्मूला जो किसी अन्य टॉनिक में नहीं. बिरली जड़ी बूटियों का सत्त. साथ ही १८ बायोकेमिकल्स, विटामिन और खनिज भी. औषधी के रूप में जाना माना, जिसकी दुनिया भर में धाक है. हर दिन के भरपूर आनन्द के लिए अनोखा ज़रिया – **ओकासा**

दवाओं की सभी प्रमुख दुकानों में

ओकासा

ओकासा की मुफ़्त पुस्तिका के लिये लिखियेः
OKASA CO. PVT. LTD. 12, Gunbow Street, Bombay 400 001.

SILVER FOR MEN – 50 TABLETS

OKASA

जाना-माना
शक्तिदायक
ओकासा
२५ दिनों के लिये असरदार
५० गोलियों के सुविधाजनक पैक में

"मेरी"

22 कैरट् स्वर्ण-आवृत जेवरों की चातुरी में है वीश्व नामी उत्तमता की प्रक्रुति। चमकीला सुन्दरी। सब की मन पसन्द, बेजाड़ रंगरूप में गारंटी जेवरों। मंगवाते वक्त जेवरों की संक्षा सचीत करे। वी.पी.पी. खर्च अलग। मुफत केटलाग के लिए लिखे।

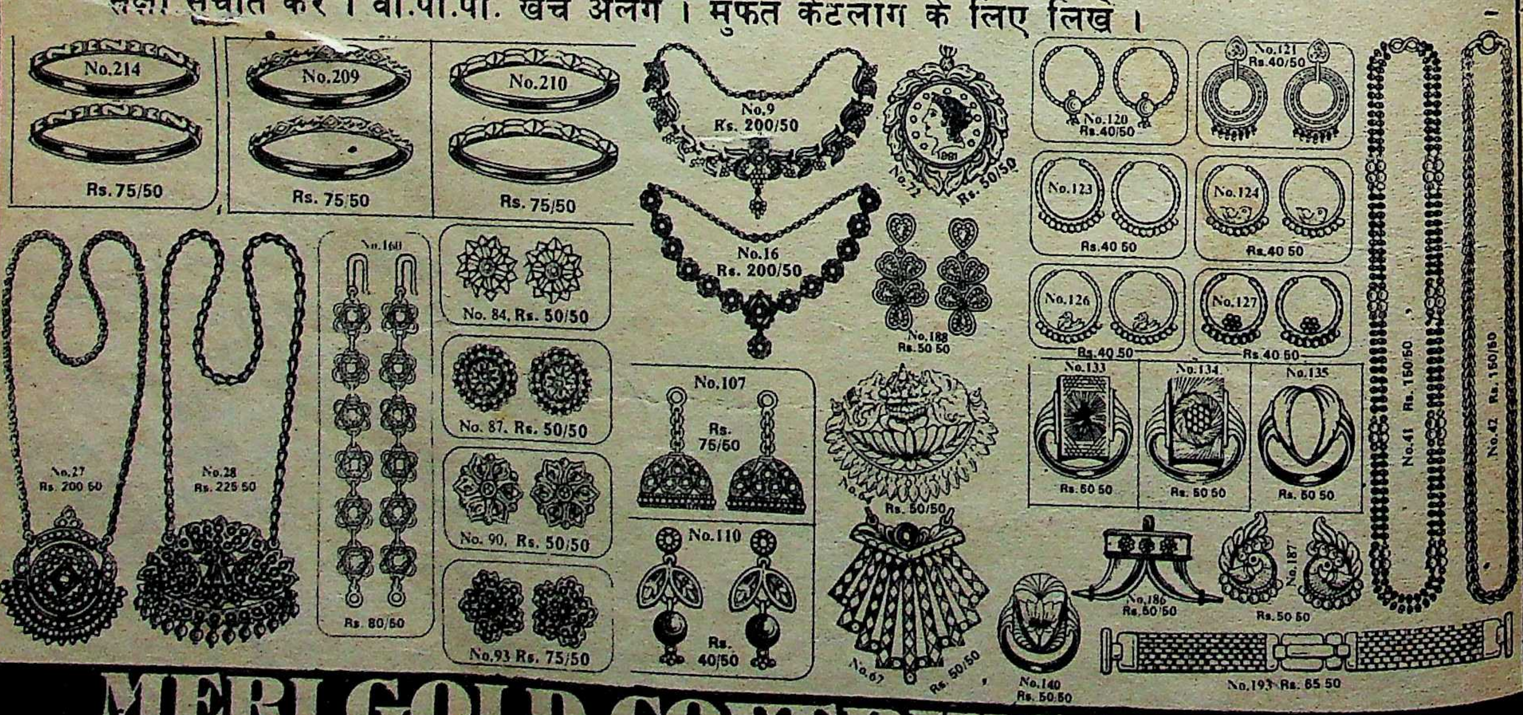
No.214
Rs.75/50
No.209
Rs. 75/50
No.210
Rs. 75/50
No.9
Rs. 200/50
No.72
1881
Rs. 50/50
No.120
Rs.40/50
No.121
Rs.40/50
No.16
Rs. 200/50
No.188
Rs.50 50
No.123
Rs.40 50
No.124
Rs.40 50
No.126
Rs.40 50
No.127
Rs.40 50
No.27
Rs. 200 50
No.28
Rs. 225 50
No.160
Rs. 80/50
No. 84, Rs. 50/50
No. 87, Rs. 50/50
No. 90, Rs. 50/50
No.93 Rs. 75/50
No.107
Rs. 75/50
No.110
Rs. 40/50
Rs. 50/50
No.133
Rs. 50 50
No.134
Rs. 50 50
No.135
Rs. 50 50
No.41 Rs. 150/50
No.42 Rs. 150/50
No.67
Rs. 50/50
No.140
Rs. 50.50
No.186
Rs.50/50
No.187
Rs.50 50
No.193 Rs. 65 50

MERI GOLD COVERING WORKS
P.O. BOX : 1405, 14, RANGANATHAN STREET
T. NAGAR, MADRAS – 600 017

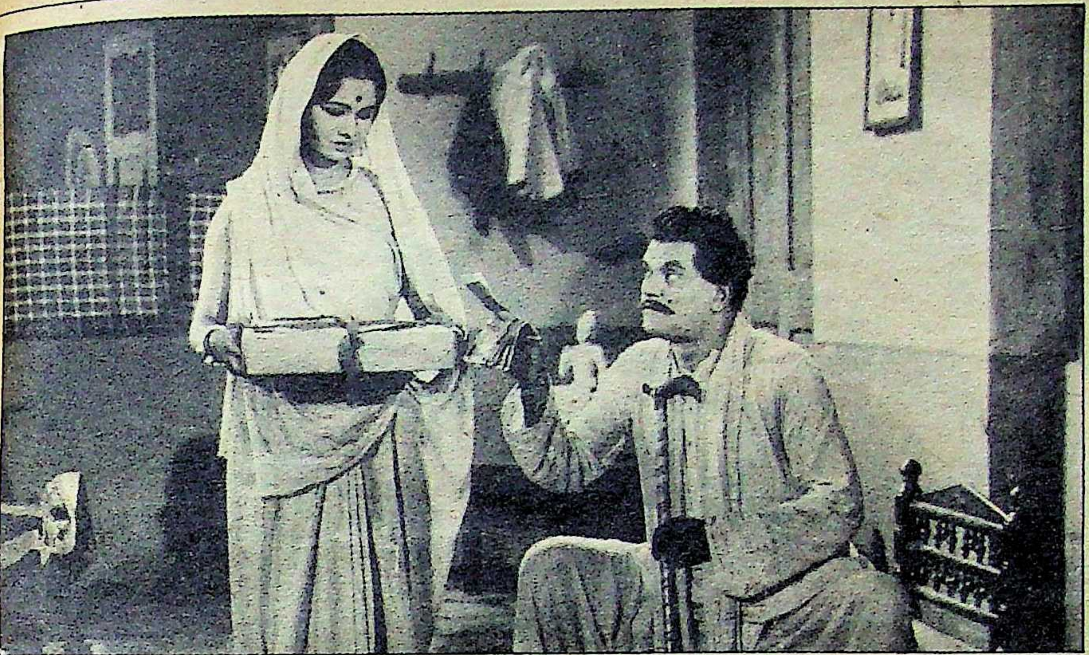

भोजपुरी फिल्मों के पच्चीस वर्षों के इतिहास की एक कड़ी: एक भोजपुरी फिल्म में एस०एन० तिवारी

यह भोजपुरी फिल्मों का दुर्भाग्य ही है कि जिस भोजपुरी को बोलने वालों की संख्या १५ करोड़ से अधिक हो और सूरीनाम, फिजी, मारीशस आदि देशों में एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती हो, उसे अपने ही देश में भाषा का दर्जा न प्राप्त हो और न ही सरकारी संरक्षण। दुर्भाग्य की बात उस समय और भी मुखर हो उठती है, जब भोजपुरी फिल्मों को सरकारी माध्यम (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) हिंदी की महज एक बोली मान कर क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में रखने से नकार देते हों और हिंदी फिल्मों की श्रेणी में रखने से कतराते हों। बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा प० बंगाल, असम, पंजाब, दिल्ली में रोजगार-व्यापार की तलाश में आकर बस गये करोड़ों लोगों की निरंतर मांग पर भी दूरदर्शन पर भोजपुरी फिल्में न तो रविवार को अपराह्न डेढ़ बजे दिखलाने की अनुमति दी जाती है और न ही रविवार की शाम को 'नेशनल नेटवर्क' पर उनको जगह मिलती है, जबकि प्रादेशिक भाषा की फिल्में हर शनिवार की शाम को और तीन महीने में कम-से-कम दो बार हर रविवार को क्षेत्रीय फिल्मों के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती हैं। और-तो-और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सरकारी माध्यम राज्य स्तर पर कोई अगुवाई नहीं करते।

प्रगति न के बराबर: भोजपुरी फिल्मों का २५ वर्षों का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जानेवाला कोई अध्याय नहीं रहा है। भोजपुरी की अपेक्षा असमिया एवं उड़िया फिल्मों ने इस अरसे में कहीं ज्यादा प्रगति की है—कथ्य की दृष्टि से भी; प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी। अन्यथा भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म १९७७ में बनने के बजाय १९६२ या ६४ में ही बन गयी होती, जब रंगीन फिल्मों का निर्माण पूरी तरह से प्रगति पर था।

किसी भी प्रादेशिक भाषा के साथ ऐसा गौरव आज तक नहीं जुड़ा, जिसकी प्रथम फिल्म ने स्वर्णजयंती मनायी हो। लेकिन भोजपुरी की प्रथम फिल्म 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबों' ने बाक्स आफिस के सारे कीर्तिमान को तोड़कर एक नहीं, कई शहरों में स्वर्ण जयंती और दर्जनों नगरों के सिनेमा घरों में रजत जयंती मनायी। ५ लाख रुपए की लागत (प्रिंट-निर्माण से लेकर प्रचार आदि खर्चों सहित) की इस फिल्म ने १९६२ में ७५ लाख रुपए से अधिक का 'बिजिनेस' किया था। 'बिजिनेस' का इतना बड़ा कीर्तिमान उस पूरे दशक में किसी भी फिल्म ने नहीं कायम किया था। लेकिन इस रजत जयंती वर्ष में न तो सरकारी स्तर पर, न ही गैरसरकारी स्तर पर 'भोजपुरी फिल्म समारोह' आयोजित किये गये और न ही दूरदर्शन ने प्रथम भोजपुरी फिल्म प्रदर्शित कर उसके गौरवशाली अतीत की याद ताजा करने की जरूरत महसूस की।

फिल्म उद्योग की जिम्मेदारी: भोजपुरी फिल्मों का विकास सही ढंग से न हो पाने के लिए समूची फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबों' की अप्रतिम व्यावसायिक सफलता ने हर ऐरे-गैरे को भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कर कुबेर बन जाने के अंध-लालच में ऐसा फंसाया कि किसी ने इसे कलात्मक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। 'सी' क्लास के फिल्म-निर्माता 'सी' क्लास की भोजपुरी फिल्में बना कर कमाये हुए धन से हिंदी में मल्टीस्टार फिल्में बनाने लगे। 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबों' के निर्माता विश्वनाथ शाहाबादी आज विनोद खन्ना और जयाप्रदा को लेकर भारी बजट की हिंदी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक (स्व०) कुंदन कुमार ने डेढ़-दो दशक पहले ही भोजपुरी का पल्ला झाड़ 'औलाद' आदि फिल्मों का निर्माण उस जमाने के सुपर स्टारों को लेकर शुरू कर दिया था। कामोबेश यही स्थिति हर भोजपुरी फिल्म निर्माता के साथ रही। भोजपुरी फिल्में बनाने वाले वे लोग रहे, जिनके पास न तो गांठ में पैसा रहा, न ही कोई योजना। वे जुआ मान कर फिल्म बनाते कि अगर बाक्स आफिस पर हिट न भी हुई, तो कम लागत के कारण निर्माण-व्यय तो निकल ही आयेगा।

यह भी महज इत्तिफाक है कि दिलीप कुमार ने संगीतकार नौशाद की सलाह पर अपनी प्रथम फिल्म 'गंगा जमना' की भाषा अवधी मिश्रित भोजपुरी रखी। 'गंगा जमना' ने भी सफलता के नये कीर्तिमान कायम किये, लेकिन उसके बाद न तो दिलीप कुमार—वैजयंती माला ने और न ही दूसरे बड़े स्टारों ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, बल्कि 'सी' ग्रेड की फिल्में मानकर उनसे परहेज करते रहे। छठे दशक में जिन-जिन कलाकारों को हिंदी फिल्मों ने 'आउट' कर दिया, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में शरण लेकर अपनी अस्मिता बनाये रखी। राकेश पांडे, अरुणा ईरानी, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार, जयश्री टी आदि कलाकार इसी श्रेणी के थे। हिंदी फिल्मों से आउट जयश्री टी भोजपुरी फिल्मों की हेलेन या हुक्कू बन गयीं, जिनके बिना वितरक फिल्म को हाथ ही नहीं लगाते थे।

"कई बार ऐसा हुआ कि भोजपुरी में फिल्म बन गयी, लेकिन मुझे फिल्म में न देखकर वितरक ने तब तक फिल्म की प्रिंट न उठाने की घोषणा कर दी, जब तक उसमें मेरा नाच नहीं हो। फलतः निर्माता को फिर से सेट बनाकर मेरा नृत्य या रोल भोजपुरी में डालना पड़ा," बताते-बताते जयश्री टी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। ठीक यही स्थिति राकेश पांडे या दूसरे 'आउट हुए' सितारों की रही।

लेकिन पिछले २५ वर्षों में, व्यावसायिक सफलता के बावजूद १९८३ और १९८६ को छोड़ दें, तो निर्माण प्रतिशत बहुत शोचनीय रहा। कम-से-कम १५० फिल्में विभिन्न कारणों से अधूरी या पूरी बन कर भी डिब्बे में बंद पड़ी रहीं। १९६७ से ७७ तक का एक दशक भोजपुरी फिल्मों के लिए असामयिक मौत का-सा काल रहा। इन दस वर्षों में कुल ४ फिल्में ही प्रदर्शित हो सकीं। इस दशक में राजेश खन्ना और फिर अमिताभ बच्चन के उदय के साथ फिल्म निर्माण की दिशा ही बदल गयी थी। इसके बाद रोमांटिक और फिर हिंसाभरी फिल्मों की गंगा में हाथ धोने के लिए भोजपुरी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक और कलाकार भी पांत बनाकर खड़े हो गये थे। भोजपुरी फिल्मों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था कि २५ वर्षों के काल में उसके जिम्मे सिर्फ ८७ फिल्में ही हाथ लगीं और इनमें से कोई भी किसी भी स्तर पर मानक नहीं सिद्ध हो सकीं।

खुशफहम शुरुआत: बिहार में सर्वप्रथम १९३१ में महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह ने एक मूक फिल्म 'पुनर्मिलन' बनायी थी। इसके बाद उन्होंने देव (औरंगाबाद) के प्रसिद्ध पर्व पर एक लघु फिल्म 'छठभइया' बनायी। इसके ३० वर्ष बाद अकस्मात भोजपुरी फिल्मों की झड़ी लग गयी। वाराणसी के कुंदन कुमार ने संगीतकार चित्रगुप्त के साथ कुमकुम और पद्मा खन्ना को लेकर 'मां' बनाया। और यह फिल्म एक तरह से इतिहास बन गयी। ५ लाख की फिल्म ने ७५ लाख का व्यापार किया। स्टंट फिल्मों की नायिका कुमकुम रातोरात भोजपुरी फिल्मों की 'नरगिस' बन गयी। १९६१ में 'गंगा जमना' बनी थी, उसकी भाषा पूर्वी जरूर थी, लेकिन उसे

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत

ASPRO
draws out pain faster

सरदर्द का
बेहतरीन
उपचार

दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा

daCunha/AS/41/87 HIN

भोजपुरी नहीं कहा जा सकता था। कायदे से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत १९६२ में 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबों' से हुई और भोजपुरी बोली से फिल्म निर्माताओं का साक्षात्कार भी।

इसके बाद तो बिहार के रामानंद तिवारी भोजपुरी फिल्म-निर्माण के क्षेत्र में कूद पड़े। उन्होंने 'लागी नाहीं छूटे रामा' भोजपुरी फिल्म बनायी। लेखक नज़ीर हुसैन थे और दिग्दर्शक कुंदन कुमार। फिल्म को अच्छी सफलता मिली। उस समय के प्रसिद्ध कमेडियन महमूद भी फिल्म में थे।

लखनऊ, वाराणसी से आये संगीतकार एंस०एन० त्रिपाठी, जिनके चित्रगुप्त सहायक रह चुके थे, ने 'विदेसिया' बनायी। बिहार वालों को निराशा हुई, लेकिन काशीवासियों ने उसे अपना लिया। कलकत्ता-बंबई के फिल्म निर्माता, जिन्हें भोजपुरी का इतना ही ज्ञान था कि शब्द के अंत में 'वा' लगा दो तो भोजपुरीं हो जायेगी, भोजपुरी फिल्मों की निर्माण-दौड़ में कूद पड़े। 'बलमा बड़ा नादान', 'जेकरे चरनवां में लागे परनवां', 'कब होइहैं गवनवां हमार' जैसी कई फिल्में बनीं, लेकिन किसी ने भी वहां की मिट्टी की सुगंध को नहीं पहचाना। राक एंड रोल और रंबा-संबा से भोजपुरी फिल्म नहीं चल सकती। उसे जरूरत थी ताल-तलैया, झोपड़ी, सादगी, लाज का घूंघट, मर्यादा और समर्पण की। इस पर खरी उतरी भोजपुरी की दूसरी फिल्म 'बिदेसिया'। इसकी कहानी समस्या-प्रधान थी। 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबों' की प्राय: सभी विशेषताएं इस फिल्म में भी दिखायी पड़ीं। 'बिदेसिया' के नायक सुजीत कुमार इस फिल्म की एक बड़ी उपलब्धि प्रमाणित हुए। इसके बाद सुजीत कुमार ने 'पान खाये सइयां' का निर्माण-निर्देशन किया और 'बलमा बड़ा नादान' में अभिनय किया। सुजीत कुमार को भोजपुरी फिल्मों का दिलीप कुमार कहा जाता है।

भोजपुरी फिल्मों के निर्माण से एक उपलब्धि यह जरूर हुई कि 'बी' और 'सी' क्लास के कलाकारों और निर्माताओं की रोजी-रोटी की समस्या हल हो गयी। आज से पांच वर्ष पूर्व बंबई फिल्म उद्योग में मंदी आयी हुई थी। भोजपुरी फिल्मों के निर्माण के कारण वह बहुत कुछ अंशों में समाप्त हो गयी।

हिंदी फिल्मों में जैसी खिचड़ी संस्कृति, माडर्न रहन-सहन व वातावरण को मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है, उसकी बू अब भोजपुरी फिल्मों में भी आने लगी। निर्माता व्यावसायिक दृष्टिकोण को रखकर भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करने लगे। १९८६ में १९ फिल्मों के प्रदर्शन तथा इनकी व्यावसायिक सफलता ने पुन: भोजपुरी फिल्मों की जैसे बाढ़-सी ला दी, जिसका परिणाम आज सामने है। बंबई में निर्माणाधीन हर १५ फिल्म में एक फिल्म भोजपुरी की है।

असफलता के कारण : साढ़े पांच हजार वर्ग मील क्षेत्र में फैले पंद्रह करोड़ व्यक्तियों की बोली भोजपुरी के फिल्मों की असफलता के पीछे कई कारण थे। फिल्म-निर्माण की बाढ़ में निर्माता-निर्देशक भूल गये कि इस भाषा-भाषी क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। इनसे परंपराओं की महानता, गीतों की सरसता, भावनाओं की सूक्ष्मता और कल्पनाओं की पवित्रता जुड़ी है। इसके विपरीत इन फिल्मों के निर्माता-निर्देशकों ने भोजपुरी फिल्म को उसी पुरानी फिल्मी लीक पर दौड़ाना शुरू किया और फिल्म में भेड़चाल की कहावत को चरितार्थ करते हुए एक तरह के फार्मूले पर बीसवीं सदी में भी वही सोलहवीं सदी की कहानियां प्रस्तुत कीं। अधिकांश गीतकारों ने बंबई में बैठे-बैठे प्रचलित लोकगीतों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें भोजपुरी के शब्दों का जामा पहनाया और अपने नाम से फिट करने लगे। संगीतकारों ने भी लोक-धुनों की द्रिशा में नयी खोज करने के बजाय भोजपुरी फिल्मों में भी उसी पाश्चात्य संगीत की शैली अपनायी और उलटफेर कर गीतों को सजाया। सबसे प्रमुख कारण था कि भोजपुरी बोली में उन लोगों ने फिल्म निर्माण किया, जिनकी जानकारी उसकी भाषा, संस्कृति और वातावरण से कोसों दूर थी। इसलिए 'कब होइहें गवनवां हमार', 'आइल बसंत बहार', 'सैंया से नेहा लगइबे', 'लोहा सिंह', 'नइहर छूटल जाये', 'सइयां से भइले मिलनवां', 'सोलहो सिंगार करे दुलहिनियां', 'बलमा बड़ा नादान', 'जेकरा चरनवां

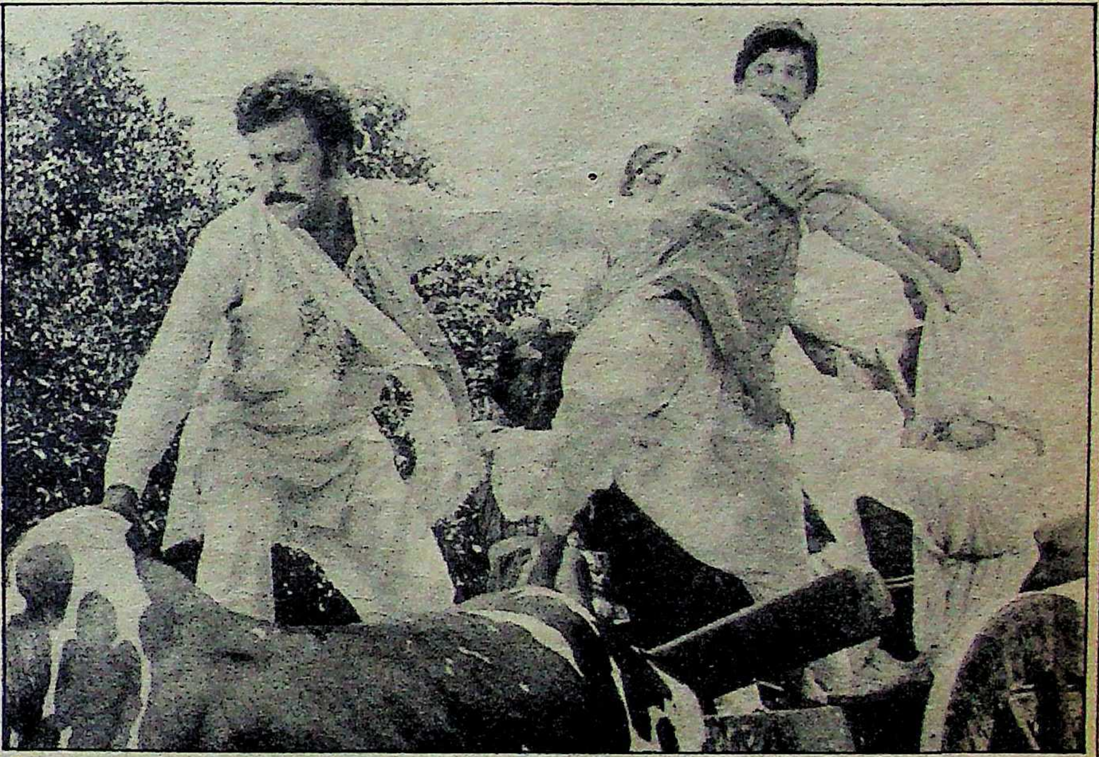

हिंदी फिल्मों का फार्मूला : 'गंगा किनारे मोरा गांव' में विजय खरे एवं कुणाल

सफल : 'लागी नाहीं छूटे रामा' में नजीर हुसेन एवं कुमकुम

में लागल परदवा', तथा 'सीता मइया' को खास सफलता नहीं मिली।

ज्यादातर पहचानविहीन फिल्में: १९८६ में तो भोजपुरी फिल्मों के निर्माण ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उक्त वर्ष में पचास से ज्यादा भोजपुरी फिल्में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरीं। कई फिल्मों के सभी गीत रिकार्ड कर लिये गये थे, तो कुछ सेंसर के लिए तैयार थीं। १९८७ में इस संख्या में और भी वृद्धि हो गयी। भोजपुरी फिल्मों के बारे में एक तथ्य यह भी है कि जो भोजपुरी फिल्में सेंसर बोर्ड से बिना किसी काट-छांट के पास कर दी जाती हैं, वे थियेटरों में चल नहीं पातीं। पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान कुछ भोजपुरी फिल्मों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जमकर व्यवसाय किया। पिछले दिनों भोजपुरी फिल्म 'दूल्हा गंगा पार का' कलकत्ता के ८ सिनेमाघरों में एक साथ लगायी गयी और खूब देखी गयी।

एक दशक के संकट के बाद प्रदर्शित भोजपुरी फिल्म 'दंगल' ने भोजपुरी फिल्मों के अंधकारमय निर्माण संसार में सफलता और आशा की नयी किरण प्रज्ज्वलित की। उसके बाद फिल्म निर्माण का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक जारी है। स्व० नजीर हुसैन की 'बलम परदेसिया' कई महीने एक ही सिनेमाघर में चलती रही। इसके बाद 'धरती मइया', 'माई के लाल' आदि फिल्मों ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की।

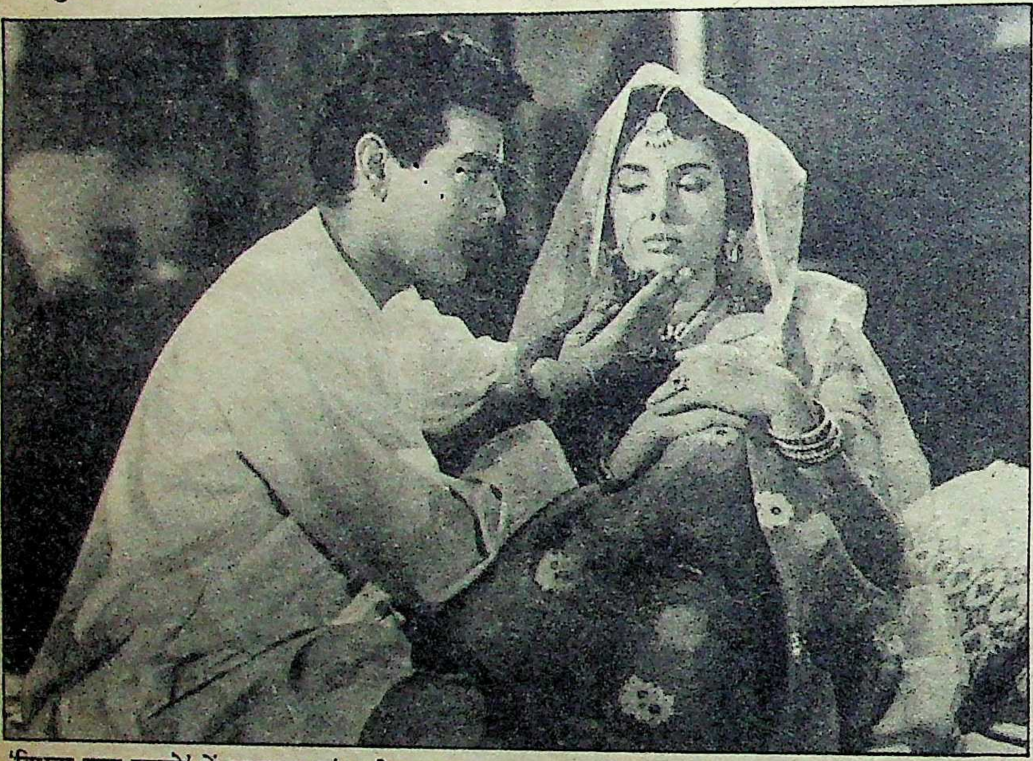
'विधना नाच नचाये' में मुमताज एवं सुजीत कुमार

माटी के गंध का अहसास: 'बिदेसिया' में नाज

'गंगा किनारे मोरा गांव', 'हमार भौजी', 'बाजे शहनाई हमार अंगना', 'गंगा-सरयू', 'बलमा नादान', 'पिया निरमोहिया', 'पिया के गांव', 'हौसला' आदि फिल्में बनीं, जिनमें 'गंगा किनारे मोरा गांव', 'पिया के गांव', 'हमार भौजी' आदि कुछ फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्में असफल रहीं। आदर्श जैन की 'राम जइसन भइया हमार', अशोक जैन की 'दुलहिन', लक्ष्मण शाहाबादी की 'दुलहा गंगा पार के', टी०पी० सिंह की 'सुहाग बिंदिया', जवाहर झा की 'गंगा की बेटी' आदि फिल्में बनीं, जिनमें से कुछ फिल्में सफल भी रहीं। इन दिनों भी कई नयी फिल्में बन रही हैं, जिन 'माई', 'दगाबाज बालम', 'राखी के लाज', 'बहुरिया', 'टूट गइल सपनवां हमार', सांच भइल सपना' आदि प्रमुख हैं।

भोजपुरी फिल्में आजकल बाजार में नहीं बिकतीं, अधिकांश निर्माताओं को स्वयं प्रदर्शित करनी पड़ती हैं। भोजपुरी के नायक सुजीत कुमार ने अपनी फिल्म में अमिताभ और रेखा को लिया फिर भी फिल्म नहीं चली। राकेश पांडे भोजपुरी दिग्दर्शक और नायक भी हैं और दूसरे नायक हैं कुणाल, जिनकी हिंदी फिल्म 'कल हमारा है' भी खूब चली थी। भोजपुरी के आज दो प्रमुख निर्माता हैं—एक हैं, मुजफ्फरपुर के झाजी जो हर तीन महीने में एक भोजपुरी फिल्म बनाने की कल्पना करते हैं और बनाते भी हैं लेकिन उनकी फिल्में सेंसर में ही लटक जाती हैं। दूसरे—जैन हैं जो नियमित फिल्में बना रहे हैं और प्रदर्शित करते हैं। राम सिंह फिल्मों के नायक भी हैं और व्यापार में भी विशारद हैं। कई निर्माताओं को भोजपुरी में लाये हैं। भोजपुरी फिल्मों में कमेडियन हैं हरि शुक्ला। वह करीब सभी फिल्मों में होते हैं। पद्मा खन्ना हिट हीरोइनों में हैं और ४० वर्ष की उम्र में भी नायिका बनी हुई हैं। अशोक जैन और मोहनजी प्रसाद सफल निर्माताओं में हैं। समीर, राममूर्ति चतुर्वेदी—लोकप्रिय गीतकार हैं। विश्वनाथ पांडे पटकथा, संवाद के लिए माना हुआ नाम है। संगीत में चित्रगुप्त, लक्ष्मण शाहाबादी, नायकों में सुजीत कुमार, राकेश पांडे और कुणाल प्रसिद्ध हैं।

भोजपुरी के कर्णधार थे नजीर हुसैन, कुंद कुमार और रामानंद तिवारी। आज केवल विश्वनाथ शाहाबादी अपने रोपे गये पौधे को फलता-फूलता देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भोजपुरी फिल्में अपनी अस्मिता के लिए आज भी संघर्षरत हैं और जब तक प्रतिष्ठित कलाकार तथा निर्देशक या रचनाशील-प्रयोगधर्मी फिल्मकार सामने नहीं आयेंगे, भोजपुरी फिल्में 'सी' श्रेणी की लक्ष्मण रेखा को तोड़कर प्रगति का सुनहरा संसार नहीं दे सकेंगी।

—बद्री प्रसाद जोशी एवं बंबई ब्यूरो

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,

विश्व-प्रसिद्ध शृंखला

पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का
एक अनूठा प्रोजेक्ट

DUPLICA

विश्व-प्रसिद्ध खोजें
विश्व-प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्य
विश्व-प्रसिद्ध रोमांचक कारनामे
WORLD FAMOUS WARS AND BATTLES
विश्व-प्रसिद्ध युद्ध
विश्व-प्रसिद्ध 101 व्यक्तित्व
विश्व-प्रसिद्ध धर्म मत एवं सम्प्रदाय
विश्व-प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी
1988
विश्व-प्रसिद्ध रिकार्ड्स
विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक
विश्व-प्रसिद्ध प्राकृतिक विनाश लीलाएं

मूल्य: 12/- प्रत्येक
डाकखर्च: 3/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें
मंगाने पर डाकखर्च माफ

- ■ प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री
- ■ प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित
- ■ सरस कथा शैली
- ■ फोटोटाइप सैट
- ■ ऑफसैट छपाई
- ■ बढ़िया कागज पर
- ■ बहुरंगी आवरण
- ■ वाजिब दाम

इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है।

कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को पूर्ण रूप से उजागर करने वाला एक सचित्र ***'मिनि एनसाइक्लोपीडिया'*** *है।*

उदाहरणार्थ *'रोमांचक कारनामे'* में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो *'खोजें'* में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। *'अनसुलझे रहस्य'* में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो *'खेल और खिलाड़ी'* व *'वैज्ञानिक'* क्रमशः जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं।

अब तक प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाड़ी 8. रिकार्ड्स (दो भागों में) 9. वैज्ञानिक 10. विनाश लीलाएं

तैयारी में/प्रेस में

■ खजाने ■ बैंक डकैतियां ■ सभ्यताएं ■ अय्याश राजा ■ प्रेम-प्रसंग ■ ठग ■ क्रान्तियां ■ दुर्घटनाएं ■ राजनैतिक हत्याएं ■ चिकित्सा पद्धतियां

फरवरी, *1988* तक प्रकाश्य

• गुप्तचर संस्थाएं • जासूस • जासूसी कांड • प्रेरक-प्रसंग

विश्व-प्रसिद्ध जासूस
जासूसी कांड
प्रेरक प्रसंग

अपने निकट के बुकस्टाल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टालों पर मांग करें अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता.

पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006

नया शो रूम : 10-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002.

VAN.PM.867

विश्व पुस्तक मेला, दिल्ली में हमारे स्टाल से १०% छूट ५/२/८८ से १५/२/८८ तक प्राप्त करें।

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत
ASPRO
drawn out pain faster
सरदर्द का बेहतरीन उपचार
दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा
daCunha/ASI/41/87.HIN

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक ३

१५ फरवरी, १९८८

माया

यह अंक

आवरण कथा

यद्यपि एमजीआर से जानकी रामचंद्रन और जयललिता के संबंध किस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, यह तो ठीक-ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन एमजीआर के जीतेजी जैसे दोनों महिलाएं उन पर अपना अधिकार जमाने में संघर्षरत थीं, ठीक वैसे ही उनके निधन के बाद उनकी उत्तराधिकारी बनने के लिए आज इन दोनों महिलाओं में भयंकर टकराव की नौबत क्यों आ गयी है? ३०

इंका संगठन
ऊपर से विशालकाय दिखनेवाला कांग्रेस संगठन अंदर-ही-अंदर खोखला हो चुका है। क्या राजीव गांधी इसे पुनर्जीवित कर पायेंगे? १४

बिहार
आंध्र में ही नहीं, बिहार में भी नक्सलवादी समानांतर सरकार चला रहे हैं। क्या बिहार में इन पर अंकुश लग पायेगा? ५३

हरिजन किधर जायेंगे?
हरिजनों को उनका हक मिला हो या नहीं, मगर चुनाव में उनका इस्तेमाल भरपूर हुआ है। अगले चुनाव में यह 'वोट बैंक' किसके हाथ लगेगा? ४२

करणा भील
विश्व प्रसिद्ध लंबी मूंछों वाले करणा भील का सिर क्या हत्यारे पाकिस्तान ले गये? ७४

राजू भटनागर
अपराधी राजू भटनागर की मौत के बाद नये सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर राजू को किसने मारा? पुलिस ने या उसके साथियों ने। ८६

राजस्थान
भाजपा राजस्थान में साफ तौर पर दो धड़ों में बंट गयी है। एक धड़ा आर०एस०एस० का पल्ला थामे रहना चाहता है और दूसरा इसका विरोध कर रहा है। ६४

दिल्ली दरबार: जाओ और सारा 'जन' मेरे नीचे करो ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
बेढब १३
प्रसंगवश: लोकसभा उपचुनाव और दिल्ली-चुनाव क्यों टाले गये? २१
तथ्यकथ्य २८
महाराष्ट्र: मराठा और दलितों के बदले हुए तेवर ४९
उत्तर प्रदेश: राजीव गांधी के गढ़ में वी०पी० सिंह ५९
उत्तर प्रदेश: पहाड़ की सुधि कौन लेगा? ६२
मध्य प्रदेश: अज्ञात बीमारी से मौत ६८
अचानक ७१
पश्चिम बंगाल: कलकत्ता के उद्योगपतियों में हलचल क्यों? ७९
अपराध: वरदराजन: एक माफिया डान का अंत ८२
विदेश ८४
परदे के पीछे ९४
फिल्म: आठवां फिल्मोत्सव: विवादों का एक तमाशा ९७
दूरदर्शन: जिंदगी: भारतीय नारी के हालात का आइना १००
अर्थतंत्र: बढ़ती जनसंख्या, घटता उत्पादन १०२

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

खयालात

अगर ज्योति बसु कांग्रेस-इ को नष्ट करने का सपना देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हम स्टेनगन संभाल लेंगे, गंगा को लाल कर देंगे।—**ए०बी०ए० गनीखान चौधरी।**

ज्योंही राजीव अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, त्योंही कांग्रेस-इ से जनमोर्चा में आने की भगदड़ शुरू हो जायेगी।—**अरुण नेहरू**

भगवान को भी यह कहने का हक नहीं कि मै राष्ट्रविरोधी हूं।—**एन०टी० रामाराव, 'संडे' में**

मैं कोई पद नहीं लूंगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति का अखाड़ा छोड़ दूंगा।—**वी०पी० सिंह, 'जनसत्ता' में**

राजनीति हमारा मिशन हो, धंधा नहीं।—**अटल बिहारी वाजपेयी, 'नवभारत टाइम्स' में**

ऐसी रिपोर्टों (ठक्कर-नटराजन आयोग की) की उपेक्षा ही इनका सबसे अच्छा इलाज है।—**न्यायमूर्ति वी०एम० तारकुंडे, 'धर्मयुग' में**

१९८७ में इसकी (भारतीय लोकतंत्र) हालत उस निस्सहाय अबला सरीखी रही, जो बलात्कार के लिए लालायित भीड़ में अकेली खड़ी हो।—**उदयन शर्मा, 'रविवार' में**

जब तक हम समाज व्यवस्था को, जिसमें मुट्ठी भर लोगों के हाथों शोषण का अधिकार हो, नहीं बदलते तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना, महज एक बकवास और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है।—**वसंत साठे, 'दिनमान' में**

गोर्बाचोव एक समर्पित कम्युनिस्ट और निर्मम अवसरवादी नेता हैं।—**'टाइम' में**

आकाशवाणी और दूरदर्शन एम०जी०आर० की मौत से इतने प्रभावित हुए कि इन माध्यमों ने क्रिसमस संबंधी कार्यक्रमों की उपेक्षाकर मानो ईशू को दुबारा सूली पर चढ़ा दिया।

—टी०वी० समीक्षक अमिता मलिक 'इंडियन एक्सप्रेस' में

संसार में हम सबसे ज्यादा अनुशासनहीन हैं और समय का पाबंद न होना हमारा आचरण है।—**फील्ड मार्शल मानेक शा**

मुझे इंग्लैंड में रहने की शर्मिंदगी है। किस कदर यह निरक्षरों का देश हो गया है।—**नीरद सी० चौधरी, 'टाइम्स आफ इंडिया' में**

जब माकपा को सलाह-मशविरा करना होता है, तो वह सीधे गोर्बाचोव के पास जाती है।—**एल०के० आडवाणी, 'टेलीग्राफ' में**

मेरी आपसे न कभी लड़ाई रही और न रहेगी। **कपिल द्वारा गावस्कर के एक सवाल पर—'स्पोर्ट्स वीक' में**

मुझे प्यार करने वाला किसी दूसरे को भी प्यार करे, शायद मैं इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।

—श्रीदेवी, 'दैनिक जागरण' में

गनीखान चौधरी

आडवाणी

श्रीदेवी

चिट्ठियां

मंदिर-मस्जिद विवाद

'माया' पाक्षिक के १५ जनवरी के अंक में सुशील श्रीवास्तव का शोध परक लेख बड़ी त्रुटियों और भ्रांतियों को लेकर एकपक्षी रीति से लिखित है, जिसके कुछ ज्वलंत प्रश्न इस प्रकार हैं:

१— लेख में बार-बार अयोध्या एवं रामजन्मभूमि की ऐतिहासिकता पर शंका की गयी है, जबकि समस्त रामभक्ति साहित्य (प्रत्येक भाषा के प्रत्येक साहित्यकारों द्वारा) में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या ही रामजन्म भूमि होनी प्रमाणित है।

२— राम भक्ति मात्र ४००-६०० वर्षों से प्रचलित है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें शहाबुद्दीन ही कर सकते हैं, अच्छा हो, यदि उन्मादी व्यक्ति के विचार न प्रस्तुत किये जायें। सैयद रामजन्मभूमि विवाद दक्षिण भारत के न्यायालय में वहां के हिंदुओं को उदारवादी समझकर ले जाना चाहते हैं, पर शायद यह उस विद्वान अधिकारी नायर को भूल गये जिसने स्वाधीन भारत में सर्वप्रथम यह स्थान हिंदुओं को सौंपा था, वह भी दक्षिण के ही थे।

३— श्रीवास्तव के अनुसार वाराणसी, मथुरा आदि की मस्जिदें मंदिर तोड़कर नहीं बनायी गयी हैं, जबकि मैंने स्वयं दोनों स्थानों के भग्न मंदिर पर निर्मित मस्जिद और अब उसके आधे भाग में हिंदू मंदिर बना हुआ देखा है।

४— श्रीवास्तव के अनुसार मुसलमान किसी के पूजास्थल पर आक्रमण नही करते। शायद इन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में न पढ़ा, न सुना। क्या आधुनिक शोधकर्ता इतना सामान्य ज्ञान भी नही रखते?

—अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, खेतान भवन, ६ माला, १९८ जे० टाटा रोड, चर्चगेट, बम्बई

'माया' का १५ जनवरी '८८ का अंक पढ़ा। सबसे अधिक प्रभावित किया आवरण कथा 'क्या मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी?' ने। यह शोधपरक लेख निश्चय ही कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा तो है ही, कम-से-कम उदारमना और सत्य-प्रेमियों की वाणी भी मुखर करने वाला है। इस पवित्र, प्रसिद्ध, ऐतिहासिक स्थान से यह शिक्षा भी तो ली जा सकती है कि राम-रहीम की भांति उनके बंदे भी साथ-साथ रहें। रही बात आधिपत्य की, तो यह स्थल भारतीयों का है—केवल हिंदू या केवल मुसलमानों का नहीं, कट्टरपंथियों/सांप्रदायिकों का तो बिलकुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए।

—डा० सुरेश चन्द्र 'निर्मल,' एफ २०० सेक्टर ३, नेहरू नगर, गाजियाबाद

आवरण कथा में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर न तो यह स्पष्ट होता है कि यह मस्जिद बाबर ने निर्मित करांई और न ही यह स्थल पूर्णत: रामजन्मभूमि की पुष्टि करता है। जो स्थिति आज है, उसे सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने उत्पन्न किया है। अत: समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि इस स्थल को 'राष्ट्रीय स्थल' घोषित किया जाये।

—राम आसरे यादव, ग्राम-पुर्वाघसा का, पोस्ट—कंचौसी, इटावा

१५ जनवरी '८८ की 'माया' में प्रकाशित लेख 'क्या मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी?' बड़ा भ्रामक है। लगता है यह लेख लेखक ने एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखा है। लेखक ने स्वयं कई जगह अपनी ही बात का खंडन किया है, जैसे प्रारंभ में लेखक रामजन्मभूमि मंदिर के आधार को मिथ, लोकगीत एवं लोक श्रुतियां मानता है और आगे जाकर स्वयं ही इसके पक्ष में लखनऊ गजेटियर तथा कनिंघम इत्यादि विद्वानों का उद्धरण देता है तथा सारी दिमागी कसरत यह सिद्ध करने में लगाता है कि वहां पहले भी मंदिर नहीं था। फिर स्वयं ही मंदिर के लिए सन १८५५ से प्रारंभ हुए संघर्षों का हवाला भी देता है।

—डा० एन०एल० गुप्ता, अलवर

'माया' का जनवरी अंक पढ़ा। जिसमें रामजन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद संबंधित लेख से बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई तथा उसमें अंग्रेजो

की भूमिका पढ़कर बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है जिससे देश में सांप्रदायिकता तथा अस्थिरता का बोलबाला है। इससे देश के विभाजित होने का संकट पैदा हो गया है। अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री पंजाब, असम यहां तक कि श्रीलंका में समझौता करा सकते हैं, तो संपूर्ण भारत के इस विवाद में क्यों रुचि नहीं लेते?

—अख्तर अब्बास, गांव मदारीपुर, पो० बिसौना, इलाहाबाद

'माया' के जनवरी प्रथम अंक में प्रकाशित आवरण कथा 'क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गयी' में आलोकजी का अनुत्तरित सवाल वाला अंश पढ़कर ऐसा लगता है कि भारत चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले, लेकिन यहां विभिन्न संप्रदाय के कट्टरपंथी हमें आपस में लड़ाकर राजनीति की गोटियां बिछाने से बाज आने वाले नहीं।

आलोकजी ने सही ही कहा है कि 'चाहे राम का मंदिर राम जन्म स्थल के ऊपर बने या वहां से १० गज या १० मील हटकर बने, इससे मंदिर की पवित्रता या ऐतिहासिकता पर कोई असर नहीं पड़ता। ईश्वर तो वास्तव में सर्वव्यापी है और भक्ति का स्थान मन में होता है।' 'माया' को इस दिशा में विशेष प्रयत्न के लिए हार्दिक बधाई।

—मनोज कुमार मिश्र 'मुन्ना,' मो० गढ़ी पुवायां, शाहजहांपुर

बाबरी मस्जिद के संबंध में जो तथ्य 'माया' ने १५ जनवरी वाले अंक में प्रकाशित किये हैं, उनसे यह तो सिद्ध नहीं होता कि उस स्थान पर मस्जिद थी या मंदिर, अलबत्ता हिंदुओं तथा मुसलमानों को यह लेख पढ़कर मानसिक कष्ट जरूर हुआ होगा। शहाबुद्दीन जैसे सस्ती लोकप्रियताप्राप्त तथा संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति का विचार प्रकाशित कर आपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है।

—सुदेश देशमुख, एच०टी०पी०डी० —२७२, कोरबा

'माया' के १५ जनवरी अंक की खोजपूर्ण आवरण कथा 'क्या मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी?' में आपने हिंदू व मुस्लिम, दोनों पक्षों को अपने अंतर्मन में झांकने की पुरजोर सलाह दी है, जो उचित प्रतीत होती है।

वर्तमान में इस विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है कि मन में यह प्रश्न बारंबार उठता है कि क्या इस विवाद का टकराव के अलावा और कोई विकल्प नहीं? इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने संगठनों की शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में अंधे होकर दोनों पक्षों को उद्वेलित कर रहे हैं।

इस विवाद का एकमात्र हल यही हो सकता है कि न तो वहां बाबरी मस्जिद रहने दी जाये और न ही रामजन्मभूमि। दोनों को तोड़कर वहां एक सुंदर बगीचा बना दिया जाना चाहिए। दो विभिन्न धर्मावलंबियों को जोड़ने के लिए यह तीसरी वस्तु ही शायद मानव जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

—मनोज पुष्प प्रजापति, विकास नगर, नीमच, मध्य प्रदेश

सिंह जेल जाने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं

१५ जनवरी, १९८८ अंक में गुलाम नबी आजाद महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस का वक्तव्य 'सिंह जेल जाने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं' पढ़ा। यह कथन पढ़ कर मुझे मारवाड़ी कहावत याद आयी 'नागी कई नावें, कई नीचोडे'। अगर गुलाम नबी आजाद में जरा भी पानी हो, तो भारत में किसी लोकसभा क्षेत्र से वी०पी० सिंह से जीत के दिखा दें। जो खरा है, उसे कोई नहीं बदल सकता।

—रामचंद्र सुथार, अनाजमण्डी, जोधपुर, राजस्थान

शाही विवाह

इधर पत्रिकाओं और अखबारों में तो होड़ लग गयी है कि ग्वालियर राजघराने के विवाहोत्सव की कौन-कितनी चर्चा कर सकता है? वस्तुतः मीडिया स्वातंत्र्योत्तर भारत का महत्व भूलकर पुनः सुदूर अतीत में जीने लगा है। हम सिंधिया की निंदा के ब्याज से क्या उनकी प्रशंसा और प्रचार में नहीं लगे हुए हैं? लगता है १९८७ की घटना (इवेंट आफ द इयर) यही विवाह है।

श्री क्षितींद्र मोहन मित्र

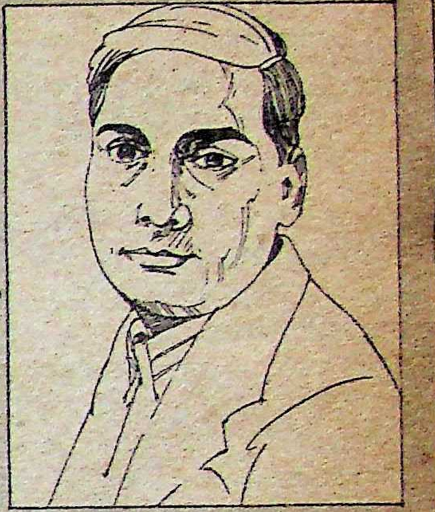

'माया बाबू' एक नाम नहीं, इतिहास है— हिंदी कथा साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता के विकास का। यों तो 'माया' के यशी संपादक का असली नाम श्री क्षितींद्र मोहन मित्र था, लेकिन 'माया' के साथ वह इतने एकाकार थे कि उनके अथक श्रम, अध्यवसाय और अप्रतिम संघर्षशीलता से जब 'माया' जनप्रिय हुई, तो वह भी जनप्रदत्त नाम 'माया बाबू' के रूप में लोकप्रिय हुए।

माया बाबू कितने मेधावी थे, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनका जन्म २९ नवंबर, १९०८ में हुआ था और उन्होंने १९२९ में यानी २१ वर्ष की अवस्था में 'माया' के प्रकाशन-संपादन का चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले लिया। वह अहिंदीभाषी थे, लेकिन हिंदी उनके लिए मात्र भाषा नहीं, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का ध्वज थी, जिसे वह 'माया' के रूप में प्रत्यक्ष योगदान देकर जन-जन के मन में फहराना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे क्रांतिकारियों की परोक्ष सहायता करके वह यूनियन जैक की जगह तिरंगे को लहराता देखने के लिए आतुर थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था में हिंदी सीखना आरंभ किया और मात्र पांच वर्ष के अंतराल के बाद उन्होंने 'माया' के संपादकीय दायित्व को संभालने के लिए अपने को सक्षम बना लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी शासन की कुनीतियों और निरंकुशता से जूझते हुए हिंदी कथा साहित्य और पत्रकारिता को जो गति, जो आयाम, जो दिशा दी, वह अपने आप में एक इतिहास है। विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कथाकृतियों को हिंदी पाठकों के सामने रखने का सर्वोपरि कार्य कदाचित माया बाबू ने ही किया। यह उनकी उदारता, सदाशयता और गुणग्राहकता का ही प्रमाण है कि तत्कालीन नवोदित से लेकर लब्धप्रतिष्ठ कथाकार तक 'माया' से जुड़े थे।

पाठकीय रुचि और आवश्यकता एवं राष्ट्रहित उनकी संपादकीय नीति के तीन प्रमुख स्तंभ थे और इन्हीं पर स्थापित है 'माया' की अक्षत विश्वसनीयता की सर्वोच्च इमारत। विश्वसनीयता का दावा नहीं किया जाता, वह अर्जित की जाती है और इसके लिए नया इतिहास रचना पड़ता है, एक नयी परंपरा का सृजन करना पड़ता है— और छह दशकों के इसी इतिहास, इसी परंपरा ने 'माया' को पहले कथा साहित्य के क्षेत्र में शीर्षस्थ होने और बाद में समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारित होने का गौरव प्रदान किया है। माया बाबू के इतिहास और परंपरा का मात्र 'माया' ही नहीं, उसकी सहोदरा 'मनोरमा' और 'मनोहर कहानियां' भी उदाहरण हैं।

एक के बाद दूसरी चुनौती को आमंत्रित करना माया बाबू का दर्शन था और यही दर्शन उनके द्वारा स्थापित 'मित्र प्रकाशन' के निरंतर विकास और विस्तार का मूल प्रेरणा-स्रोत है। मनुष्य की काया चिरजीवी नहीं होती, लेकिन उसका दर्शन कालजयी होता है। यही कारण है कि ११ फरवरी, १९५७ को माया बाबू के भौतिक साहचर्य से वंचित हो जाने के बावजूद उनका दर्शन मित्र प्रकाशन का निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है। आज मित्र प्रकाशन देश का अग्रणी पत्रिका प्रतिष्ठान है जो 'माया', 'मनोरमा', 'मनोहर कहानियां', 'सत्यकथा', 'प्रोब इंडिया' (अंग्रेजी), 'आलोकपात' (बंगला), 'मनोरमा' (बंगला), जैसी लोकप्रिय और बहुप्रसारित पत्रिकाएं अत्याधुनिक तकनीक के जरिये प्रकाशित करके सुधी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है।

११ फरवरी, १९५७ को 'माया' के प्रातःस्मरणीय संस्थापक माया बाबू की ३१वीं पुण्य तिथि है। इस अवसर पर पत्रकारिता के शलाका पुरुष को 'माया' परिवार का शत शत प्रणाम!

जाओ और सारा 'जन' मेरे नीचे करो

लक्ष द्वीप के निर्जन टापू से जब दिल्ली दरबार साले-सालियों के साथ विहार करके जनसंकुल दिल्ली में आये, तो अमेठी में राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह एक लाख जन की पाठशाला लगाये, प्रश्नावली हाथ में लिए मौखिक परीक्षा ले रहे थे। उनके पास बहुत से प्रश्न थे, उनमें एक था कि रक्षा सौदों (बोफोर्स और पनडुब्बी) में भारी दलाली किसने खायी? जन का समवेत स्वर था, "दलाली उसने खायी।" दिल्ली दरबार ने तुरन्त जार्ज को टेलीफोन पर शंकरानंद को टपकने का आदेश दिया। शंकरानंद बंद गले के कोट का आखिरी बटन बंद किये बगैर टेलीफोन पर टपक लिये, तो दिल्ली दरबार गरजे, "वह अभी तक बोफोर्स की रिपोर्ट इस मूर्ख जन को मूर्ख बनाने के लिए क्यों नहीं दी। देखा, वह राजा मांडा मेरी अमेठी में जन की सामूहिक मौखिक परीक्षा में क्या पूछ रहा है कि रक्षा सौदों में किसने दलाली खायी? तुम्हारी वजह से यह हो रहा है। फौरन रिपोर्ट दो कि कोई चोर नहीं है।" शंकरानंद ने घबराहट में टेलीफोन के चोंगे को संभालते हुए कहा, "सर, वह आपने ही कहा था कि ठक्कर-नटराजन की फेयरफैक्स रिपोर्ट में मैंने राजा मांडा को फंसा दिया है। इस बीच अपनी बोफोर्स रिपोर्ट रोके रहो। इसीलिए मैं उसे रोके हुए हूं।" दिल्ली दरबार फिर गरजे, "हां, वह तो कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि वह अजिताभ बच्चन को पाक-साफ दिखाने वाली रिपोर्ट इस बीच में आ जानी चाहिए, ताकि मैं अपने अमित को इलाहाबाद से फिर से जिताकर ससद में ले आऊं। लेकिन उस गोपी ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। इसीलिए मैंने उसको अपने यहां से शंट कर दिया। शंकरानंद याद रखना, अगर तुमने बोफोर्स रिपोर्ट में और देरी की, तो मैं वह तुम्हारा जल स्रोत का मंत्रालय 'सेफ कस्टडी' से निकाल कर किसी को थमा दूंगा और तुमको डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा।" शंकरानंद को कड़कड़ाती ठंड में ठंडा पसीना आ गया और उनकी तलवार कट खिजाबी मूंछों से सफेदी झांकने लगी। दिल्ली दरबार की तरफ से टेलीफोन का चोंगा धड़ाम से पटक दिया गया, लेकिन शंकरानंद के हाथ में टेलीफोन का चोंगा अनमना-सा कान में ही चिपका रहा। इसी बीच हिंदुजा बम्बई के समुद्र में खड़े ब्रिटेनी जहाज में अपनी बेटी के हाथ पीले करके शंकरानंद के कमरे में आ गिरे। बंदहवास शंकरानंद के हाथ से टेलीफोन का चोंगा रिसीवर पर रखते हुए हिंदुजा ने बिजली के मेनस्विच पर हाथ मारा और अपने साथ शंकरानंद को घुप अंधेरे में डुबा दिया। शंकरानंद चिल्लाये, "अरे-अरे यह मेरे साथ अंधेरे में क्या करने का इरादा है।" हिंदुजा की भारी भरकम आवाज थी, "शंकरानंद हम तो धवन के समय से सब कुछ अंधेरे में करते आ रहे हैं। तुम लोगों ने अंधेरे का काम उजाले में करना शुरू कर दिया है। इसीलिए कमीशन पर कमीशन बनाना पड़ रहा है।" घुप अंधेरे में हिंदुजा की काली आकृति देखकर शंकरानंद की अक्ल गुम हो गयी और उन्होंने घबरा कर काला बुरका पहन लिया, "अरे हिंदुजा भाई, कुछ तो इस शंकरानंद का खयाल किया होता। आखिर मैं बोफोर्स की संसदीय समिति का चेयरमैन हूं। माना तुम दिल्ली दरबार की परमीशन लेकर आये हो। आना था तो लुकछुप कर रात के तीसरे पहर आते। तुम तो रात के पहले ही पहर में आ धमके।" हिंदुजा ने बुरके को उठाने के उपक्रम में शंकरानंद की गठई (गर्दन) पकड़ ली, तो शंकरानंद चिल्ला पड़े, "अरे रिपोर्ट में जो चाहो लिखा लो, लेकिन गला तो न घोटो।" खुद ही शंकरानंद ने बुरका हटाकर अपना कान हिंदुजा के मुंह में फिट कर दिया। उसके बाद हिंदुजा की थूक मिश्रित फुसफसाहट शंकरानंद के कान से घंटों निगलते रहे।

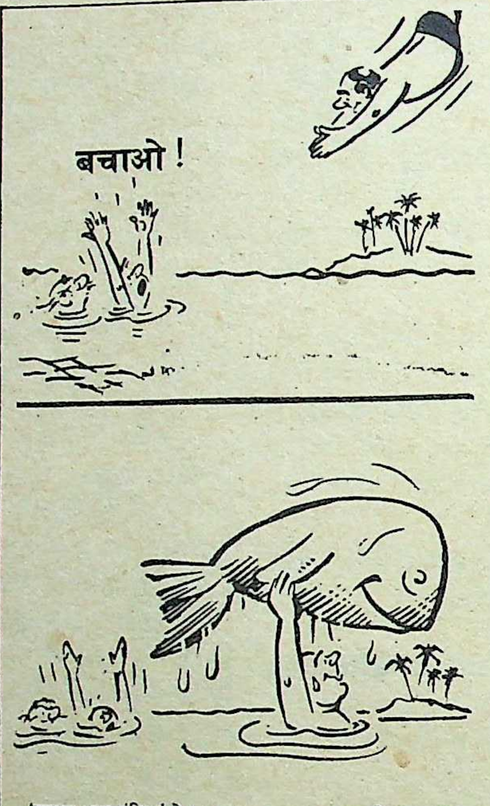

'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

आर०के० लक्ष्मण

दूसरी ओर दिल्ली दरबार में हुजूम इकट्ठा होने लगा। मारग्रेट अल्वा 'कबड्डी-कबड्डी' करती हुई आयीं और पी०वी० नरसिम्हाराव की बूढ़ी पीठ पर चढ़ बैठीं। जब राजेन्द्री वाजपेई ने दिन दहाड़े यह हुड़दंग देखा, तो आग बबूला होकर बोलीं, "माना अभी ढली नहीं हो। लेकिन दरबार में खुलमखुल्ला लड़कियों की यह गुंडई मैं बरदाश्त नहीं कर सकती हूं। आखिर मैं मुल्क की समाज कल्याण मंत्री हूं।" पास खड़े बसंत साठे ने साठे पर पाठा मारते हुए कहा, "राजेन्द्रीजी जाने भी दीजिए। यह आपकी तरह भागलपुर में नहीं पैदा हुईं। यह तो मंगलौरी-बंगलौरी है। इसके अलावा यह करेला नीम चढ़ा है यानी खेल-कूद मंत्री है यह। आपकी तरह मास्टरनी थोड़े ही रही।" भागलपुर की याद दिलाते ही राजेन्द्रीजी अपने बचपन की यादों में डूबने-उतराने लगीं तो साठे मारग्रेट अल्वा की तरफ 'लस' लिये, "क्यों इतना चुलबुला रही हो, बेबी। क्या ले आयी हो?" अल्वा 'बेबी' के सम्बोधन से रूठते हुए बोलीं—"साठे अंकल, आप मुझे बेबी न कहा करें।" साठे ने दुलार से कहा, "रूठा न करो। अगर तुम मुझे साठे अंकल कहना छोड़ दो मैं तुमको बेबी कहना छोड़ दूंगा। अच्छा यह बताओ कि क्या खुश-खबरी लायी हो!" अल्वा ने उझलते हुए कहा, "अंकल...सारी साठेजी, आपको नहीं मालूम दिल्ली दरबार को वीर बच्चे का पुरस्कार मिल गया है। इसे हम लोग २६ जनवरी को हाथी पर बिठा कर गणतंत्र दिवस की परेड में निकालेंगे।" साठे ही नहीं, बल्कि आस-पास खड़े कई दरबारी सठिया गये कि आखिर दिल्ली दरबार ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि उनको 'वीर बच्चों' की लाइन में खड़ा किया जा रहा है। जब सबकी आंखों में प्रश्न चिह्न उभर आया, तो अल्वा ने खुशी से अपने को उछालते हुए कहा, "बूझो तो जानें। दिल्ली दरबार को वीर बच्चे का राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला?" सब पहेली को बुझाने में डूबने लगे। लेकिन कोई भी पहेली बुझाने में कामयाब नहीं हो पाया, तो अल्वा ने फुदक कर कहा—"हार..." सभी ने 'हां' के लिए मुंड़िया हिला दी, तो अल्वा ने चहक कर कहा—"क्या तुम लोगों को पता नहीं, जब दिल्ली दरबार अभी लक्ष द्वीप गये थे, तो उन्होंने समुद्र में कूद कर एक व्हेल मछली को बचाया था। मछली को बचाने के लिए ही उनको वीर बालक का पुरस्कार दिया जा रहा है।" अल्वा की बात सुनकर पूरा दरबार खुशी से झूम उठा और गगनभेदी जयजयकार होने लगी—"वीर बालक

दिल्ली दरबार जिंदाबाद।" प्रोफेसर एन०जी०रंगा तो आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर सुझाव दिया, "अगर इस बार संभव न हो, तो अगली २६ जनवरी को उन सांसदों को भी वीर बालक का पुरस्कार मिलना चाहिए जो मंत्रिपद पाने के चक्कर में काफी लम्बे अर्से तक अपने घरों में बैठे मक्खी मार रहे हैं। मक्खी स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको मारना राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में वीरतापूर्ण रचनात्मक सहयोग है।" पी०वी० तो कुछ बोले नहीं, लेकिन सरोज खापर्डे ने तुरन्त अपने जूड़े के घोंसले को और ऊंचा करके आवाज लगायी—"इधर आइए, इधर आइए। मुझे आप लोग अपना मक्खी मारने का हिसाब-किताब दीजिए।" तीन-चौथाई भीड़ तो सरोज की तरफ बढ़ी, लेकिन एक चौथाई ने रुक कर उनसे सवाल पूछ लिया, "तुम्हें हम लोग अपनी मक्खियों का हिसाब क्यों दें? हम लोग सीधे दिल्ली दरबार को देंगे।" सरोज खापर्डे ने चट से अपने पर्स से लिकमे का गुलाबी फेस पाउडर निकाल कर अपने चेहरे पर मला और क्रुद्ध होकर बोली, "मुझे मक्खियों के मारने का हिसाब नहीं दोगे, तो किसको दोगे। मुल्क चलाने की एक सवैधानिक व्यवस्था है। काम उसी के अनुरूप होगा। दिल्ली दरबार ने हजारों बार एलान किया है कि चाहे वह पंजाब का समझौता हो या मिजोरम का, सब कुछ संविधान के 'फ्रेमवर्क' में ही होगा। मैं मुल्क की स्वास्थ्यमंत्री ही नहीं, बल्कि 'कन्या कुआरी' भी हूं। तुम लोगों को अपना मक्खी मार रिकार्ड मुझे ही देना होगा, क्योंकि यह संविधान सम्मत है। एक चौथाई इंकाई सांसद बगलें झांक कर तीन चौथाई सांसदों की भीड़ में शामिल होकर अपना-अपना 'मक्खी मार रिकार्ड' सरोज खापर्डे को थमाने लगे।

सरोज खापर्डे ने सांसदों के 'मक्खी मार दावे' पहले दोनों हाथों से थामने शुरू किये। लेकिन जब वे हाथों के काबू के बाहर हो गये, तो उन्होंने पैरों और मुंह से दबाना शुरू कर दिया। दावों के साथ नोट भी लगे थे, उन्होंने कुछ तो रखे, जब वे बहुत अधिक होने लगे तो वह चिल्ला पड़ीं—"घूस देने और लेने की हम लोगों ने कितनी-कितनी नयी टेक्नोलाजी का आयात किया। आप लोगों के कितने पाठ्यक्रम कराये। लगातार इस काम के लिए वर्कशाप चल रही है। लेकिन आप लोगों ने लगता है कि कुछ नहीं सीखा। इसी समय सुरक्षा की काली बिल्लियों ने तेजी से आकर सरोज खापर्डे को मय सांसदों के हुजूम के एक ओर धकिया दिया। दिल्ली दरबार के आगमन की लाल-पीली-नीली बत्तियां जल उठीं। पूरे दरबार में गहन सन्नाटा छा गया।

दिल्ली दरबार के आते ही फरशी सलामों की (बोफोर्स) तोपें धड़ाधड़ दगने लगीं। दरबार में दरबारियों के भारी हुजूम को देखकर दरबार ने पास खड़े जार्ज से पूछा, "ये लोग क्या चाहते हैं?" जार्ज ने अदब से झुककर कहा, "सर ये लोग आपकी लक्ष द्वीप पिकनिक के लतीफे सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। बड़ी मुश्किल से ये इकट्ठा हो पाये हैं। कहते हैं कि लतीफे सुनते-सुनते इनके कान बहरे हो गये। अब कुछ हकीकत सुनना चाहते हैं।" दिल्ली दरबार ने कहा, "ठीक है, ठीक है। आज मैं इन लोगों को सच्चे लतीफे सुनाऊंगा।" पीछे खड़ी सरला ग्रेवाल ने दिल्ली दरबार के हाथ में एक कागज पकड़ा दिया तो दिल्ली दरबार ने लतीफे सुनाने की मुद्रा को छोड़कर तुरन्त एलान किया, "लतीफे मैं बाद में सुनाऊंगा। मेरे सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं। इनको लेकर आप लोगों को जेहाद छेड़ना है। उनमें से एक यह है कि जब लक्ष द्वीप से मेरा यार यानी अमि यानी अमिताभ बच्चन मेरी ससुराल को हेलीकाप्टर से लेकर कोचीन में उतरा और कार में बैठने लगा, तो गोयनका यानी एक्सप्रेस के फोटोग्राफर ने उसकी फोटो उतार ली। जब अमि ने 'मर्द' स्टाइल में उतर कर फोटोग्राफर को फाइट मारी तो जवाब में उसने मेरे अमि को पटकनी दे दी। यह अमिताभ पर हमला नहीं है, मेरे ऊपर हमला है। सारे राष्ट्र पर हमला है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आप लोगों को सारे मुल्क में इस हमले के खिलाफ एक भयंकर तुफान खड़ा कर देना है।" दिल्ली दरबार में टेप बजा कर उसका समर्थन कराया गया और नारे लगवाये गये कि "हम लोग खून की एक-एक बूंद बहा कर इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेंगे।" तभी दिल्ली दरबार तुरन्त दूसरे मुद्दे पर आ गये—"उपेन्द्रा का हैदराबाद हवाई अड्डे पर मेरी बीवी ने अपमान किया। किसी का मान और अपमान करना मेरा और मेरे परिवार का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए कोई 'चूं' नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। अवसर आने पर यह मामला मैं किसी अन्तरराष्ट्रीय मंच पर उठाकर उपेन्द्रा की ऐसी तैसी कर दूंगा। इस समय मेरे सामने उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मेरी अमेठी में राजा मांडा कैसे घुसा? वहां जाकर वह एक लाख की भीड़ कैसे जुटा पाया? मुझे इसका इसी क्षण उत्तर चाहिए। यह भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है।" दिल्ली दरबार आग बबूला होकर इधर-उधर देखने लगे, "वह के०एन० सिंह कहां है। उसने कहा था कि मुझे आप पार्टी का महामंत्री बना दीजिए, मैं राजा मांडा को अमेठी क्या उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दूंगा।" भीड़ में लुके-छुपे के०एन० सिंह को सुरक्षा की काली बिल्ली ने धर दबोचा और दरबार के सामने हाजिर कर दिया। के०एन० सिंह को जब दिल्ली दरबार ने आग उगलती आंखों से घूरा, तो वह मिनमिनाने लगे, "सर, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूं। मुझसे यह सारा काम गुलाम नबी आजाद ने यह कह कर छीन लिया कि तुम पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए साम्यवाद और समाजबाद का नारा लगाओ। मैं यू०पी० देख रहा हूं।" दिल्ली दरबार दहाड़े, "कहां है वह गुलाम का बच्चा।" सुरक्षा की काली बिल्ली गुलाम नबी पर लपके कि उसके पहले ही वह अपनी फर की टोपी उतार कर सामने कटघरे में आ गये, "हुजूर इसमें मेरा दोष नहीं है। यू०पी० में भीड़ जुटाने का थोक व्यापार वीर बहादुर सिंह ने अपने हाथ में ले रखा है। लगता है कि राजा मांडा से कमीशन खाकर उसी ने अमेठी में भीड़ जुटाई है। मैंने तो राजा मांडा को ऐसी औकात पर पहुंचा दिया था कि धारा ११४ को तोड़ने के लिए उसको पांच आदमी नहीं मिल पा रहे थे।" दिल्ली दरबार फिर दहाड़े, "वह वीर बहादुर कहां है! उसको मेरे सामने हाजिर करो।" सुरक्षा की काली बिल्ली ने इधर-उधर ही नहीं, बल्कि लखनऊ और गोरखपुर में भी मुंह मारा। लेकिन वीर बहादुर का कहीं पता नहीं चला। इसी बीच बूटा सिंह ने मरी हुई आवाज में आगे बढ़कर कहा, "सरकार, वीर बहादुर का कहीं पता नहीं चल रहा है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में वीर बहादुर के गुम होने की रिपोर्ट लिखा दी गयी।"

जब लक्ष द्वीप से
मेरा यार यानी अमि यानी
अमिताभ बच्चन मेरी ससुराल को हेलीकाप्टर
से लेकर कोचीन में उतरा और कार में बैठने
लगा, तो गोयनका यानी एक्सप्रेस के फोटोग्राफर
ने उसकी फोटो उतार ली। अब अमि ने 'मर्द'
स्टाइल में उतर कर फोटोग्राफर को फाइट
मारी, तो जवाब में उसने मेरे अमि को पटकनी
दे दी। यह अमिताभ पर हमला नहीं है, मेरे
ऊपर हमला है। सारे राष्ट्र
पर हमला है।

दिल्ली दरबार उठते-उठते फिर दहाड़े, "मैं चार-छह दिन के लिए साले-सालियों के साथ पिकनिक मनाने लक्ष द्वीप के निर्जन टापू में क्या चला गया, सारा 'जन' तुम लोगों ने मेरे नीचे से खिसका दिया। चलो जाओ और सारा 'जन' मेरे नीचे करो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं है।" दिल्ली दरबार आहिस्ता-आहिस्ता भारी कदमों से अपनी आरामगाह की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें अहसास होने लगा कि "कहीं जन से निर्जन में जाना मुझे काफी महंगा तो नहीं पड़ा!" तभी दिल्ली दरबार को जयजयकार का टेप चलाकर इस अहसास से मुक्त करा लिया गया।

—[illegible]

विचार कम हादसे ज्यादा

इंका कार्य समिति की पिछली बैठक की 'प्रेस ब्रीफिंग' में पार्टी के महामंत्री गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं को बताया कि करीब आधे दर्जन विषयों (बेरोजगारी, पंजाब-असम समस्या, सांप्रदायिकता, संगठन तथा देश की राजनीतिक स्थिति आदि) पर विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि पार्टी के सदस्यता-अभियान का विषय ही पूरे चार घंटे खा गया। बाकी किसी विषय को लिया ही नहीं गया।

जानकार सूत्रों का कहना है कि जब पार्टी के सदस्यता-अभियान पर बहस चल रही थी, उस दौरान केंद्रीय ऊर्जामंत्री बसंत साठे और पार्टी के बुजुर्ग नेता कमलापति त्रिपाठी में काफी तकरार हो गयी। त्रिपाठीजी यह जानना चाहते थे कि पिछले सदस्यता-अभियान में पार्टी के पास जो दो करोड़ रुपए एकत्र हुए थे, उनका क्या हुआ? क्या पिछली सदस्यता रद्द कर दी गयी है? अगर ऐसा हो गया है, तो उस राशि को कैसे लौटाया जायेगा? इस बात पर साठे साहब बिगड़ गये कि त्रिपाठीजी आप पूरी स्थिति की जानकारी लिये बिना इस तरह के प्रश्न उठाकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

जब साठे और त्रिपाठी में गरमागरम बहस हो रही थी, उस समय राजीव गांधी मात्र मुस्करा रहे थे। बाद में त्रिपाठीजी चुप हो गये।

इसी बैठक में जब तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री एम०जी० रामचंद्रन को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी खड़े हुए, तो केंद्रीय कृषिमंत्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लों उठने के चक्कर में औंधे मुंह गिर पड़े। ढिल्लों का एक हाथ पिछले दिनों टूट गया था। उसमें प्लास्टर बंधा हुआ था। उनको एक ओर केंद्रीय वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी तथा दूसरी ओर केंद्रीय आवासमंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई सहारा देकर उठा रही थीं कि संभल न पाने के कारण वह औंधे मुंह गिर पड़े। उनके गिरते ही कई लोग तुरंत दौड़े और उनको उठा लिया।

इंका कार्य समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को डिनर दिया था। केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण प्रधानमंत्री निवास से निकल कर बाहर लान में लगाये गये पंडाल में आ रहे थे जहां डिनर की व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री निवास में पारदर्शी शीशे के दरवाजे हैं। करुणाकरण को अंदाज नहीं हो पाया और वह एक शीशे के दरवाजे से इतनी जोर से टकरा गये कि तुरंत लहू-लुहान होकर अस्पताल पहुंच गये। बताया जाता है कि करुणाकरण के सिर में कई टांके लगे।

इंका महामंत्री गुलाम नबी आजाद ने दूसरे दिन 'प्रेस ब्रीफिंग' में जो उस शाम हुआ, वह तो नहीं बताया, लेकिन वह सब बता दिया जो कार्य समिनि की बैठक में कतई नहीं हुआ।

योजना आयोग का 'लाई डिटेक्टर'

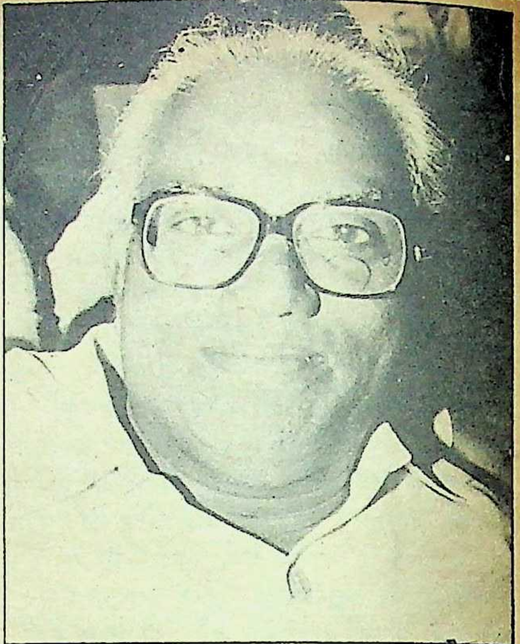

केंद्रीय योजना आयोग एक ऐसा 'लाई डिटेक्टर' तैयार करने की स्थिति में आ गया है, जिससे वह इस बात का पता लगा ले कि सूखा और बाढ़ के लिए विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दावों में कितना झूठ बोलती हैं। इसके लिए आयोग जल्दी ही कुछ बहुत अच्छे किस्म के कंप्यूटरों का आयात भी करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार इस काम के लिए इस बजट में आयोग को अच्छा-खासा पैसा भी देने जा रही है।

पिछले दिनों योजना आयोग ने सूखा राहत कार्यों की समीक्षा करने के दौरान पाया कि सूखे और बाढ़ की आड़ में राज्य सरकारें अपने नुकसान के आंकड़े बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताकर केंद्र से काफी ज्यादा रकमें वसूल लेती हैं। उसके बाद वह उस राशि का इस्तेमाल दूसरे मदों में करके यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि राज्य सरकारों ने सूखा या बाढ़-कार्य बहुत ही अच्छी तरह किया। उससे कृषि-उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आ पायी। केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है; जिससे वह वस्तुस्थिति का ईमानदारी से जायजा ले सके। अंत में उसे राज्य सरकारों की ही रिपोर्ट कुछ टीका-टिप्पणी के साथ स्वीकार कर लेनी पड़ती है।

भारत सरकार के निर्देश पर पिछले दिनों योजना आयोग के अलावा कई अन्य आर्थिक विषयों से संबद्ध विशेषज्ञों ने इस बात पर विचार किया कि राज्य सरकारों की इस धोखाधड़ी को कैसे रोका जाये? उ०प्र० सहित कई राज्यों ने शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे की पृष्ठभूमि में इस आशय की रिपोर्ट केंद्र को दी कि लगभग ३० प्रतिशत खेतों में बुआई ही नहीं हो पायी है। लेकिन जब इन राज्य सरकारों ने अपने कृषि उत्पादन के आंकड़े दिये, तो गत वर्ष की तुलना में अधिक पैदावार की बातें कहीं। इसी के साथ सूखा राहत कार्य के लिए मिली केंद्रीय मद का ये सरकारें औसतन २० से ३० प्रतिशत ही खर्च कर पायीं। बाकी पैसा अन्य मदों में खर्च कर लिया। अर्थशास्त्रियों ने इसका यह अर्थ निकाला कि इन सरकारों ने सूखे की जितनी भयावह स्थिति बतायी थी, वास्तव में उतनी नहीं थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ३० प्रतिशत खेतों में बुआई नहीं हो पायी, तो कृषि उत्पादन में पूर्व वर्ष की अपेक्षा अधिक पैदावार कतई नही हो सकती है।

योजना आयोग ने इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकारें अपने दावे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। इसीलिए राज्यों की इस बात की वार्षिक योजनाओं में योजना आयोग उतनी बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, जितनी उसने पिछले सांलों में की थी। योजना आयोग बड़े पैमाने पर कंप्यूटर लगाने जा रहा है, ताकि राज्य सरकारें केंद्र से झूठ न बोल पायें। वस्तुतः यह एक तरह का 'लाई डिटेक्टर' होगा जो राज्य सरकारों का झूठ पकड़ेगा। ■

भारतीयता के प्रतीक और देश के 'जय जवान, जय किसान' के मूल मंत्र के जनक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की २२वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ११ जनवरी, १९८७ को सारे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके पुत्र सुनील शास्त्री (पूर्व ऊर्जामंत्री, उत्तर प्रदेश) द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक पुस्तक 'लाल बहादुर मेरे बापूजी' का श्रीमती ललिता शास्त्री द्वारा विजय घाट पर विमोचन भी हुआ। 'माया' परिवार भी देश के प्रिय नेता को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चित्र : (पुस्तक विमोचन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति वेंकटरमन और स्वर्गीय शास्त्रीजी के बड़े पुत्र और सांसद हरिकृष्ण शास्त्री)।

छाया : सुनील

क्या आप कल्पना कर सकतें हैं कि घने जंगल में मोहक बाघ आपको दिखे और आप उसे खुली जीप में बैठ कर निहारते रहें? वह सांभर या चीतल का शिकार करे और आप दिल थाम कर देखते रहें? निश्चित रूप से अरावली एवं विंध्याचल की पर्वत शृंखलाओं के मध्य रणथम्भौर के वनक्षेत्र में विकसित बाघ परियोजना में ऐसे दृश्य 'माया' ने अपने फोटोग्राफर के साथ स्वयं देखे हैं।

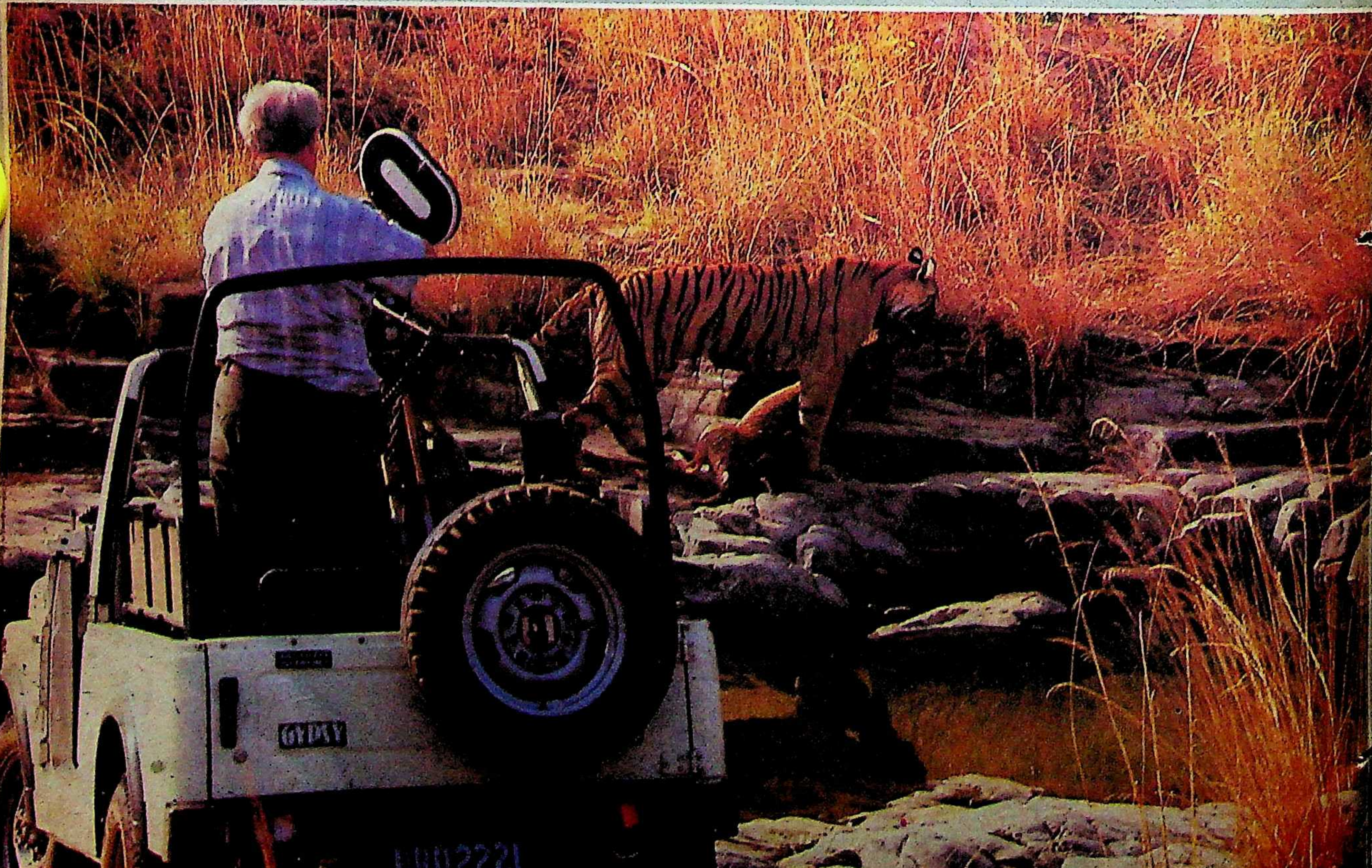

सवाई माधोपुर से १५ किलोमीटर दूर स्थित अभयारण्य में पहुंचने पर अहसास होता है कि आदमी की निगाह प्रकृति को मापने के लिए कितनी छोटी है। सवाई माधोपुर पहुंचने पर यह अहसास ही नहीं होता कि कहीं पास में ही रणथम्भौर का अभयारण्य होगा, घाटियां होंगी, पहाड़ होंगे। पर १५ किलोमीटर दूर ही वातावरण बदल कर प्रकृति अपने ऐसे रूप के दर्शन कराती है कि मन खिल उठता है। अभयारण्य के एक ओर चोटी पर रणथम्भौर का उजड़ा ऐतिहासिक गढ़ नजर आता है, तो दूसरी ओर बाघ परियोजना का द्वार। यहीं से शुरू होती है ३९२ वर्ग किलोमीटर में फैली बाघ परियोजना। इसके मुख्य द्वार से सटा हुआ है, वह जोगी महल, जिसमें कभी रणथम्भौर स्थित गणेश मंदिर का पुजारी रहा करता था और अब वन विभाग का रेस्ट हाउस है। इसी रेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने दोस्तों के साथ अपनी थकान उतारी थी।

परियोजना प्रबंधकों ने अभयारण्य में दो सौ किलोमीटर लंबा ऐसा रास्ता बना रखा है, जिसमें जीप पर सवार होकर जाया जा सकता है। ऐसे ही एक रास्ते पर खुली जीप में जब हम बाघ दर्शन के लिए रवाना हुए, तो कहा यह जा रहा था कि आज बाघ दर्शन की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल, झीलों के मुहानों पर स्वच्छन्द विचरण करते सांभर, चीतल, नील गायों के झुण्ड-के-झुण्ड नजर आये, तो पहाड़ियों के ऊपर इधर-से-उधर मुंह मारते जंगली सुअर दिखे। इन जानवरों का स्वच्छन्द विचरण बता रहा था कि बाघ के दर्शन होना मुश्किल है। पर जोगी महल से १५ किलोमीटर आगे चलते ही एक बरसाती नदी के ठहरे पानी के इर्द-गिर्द फैली हरियाली के बाहर जो दृश्य नजर आया, उससे जीप स्वतः ही बंद हो गयी। दो साल की उम्र का छह फुटा बाघ नदी के किनारों पर उग आयी घास चरते चीतल झुण्ड पर ऐसा झपटा कि पलक झपकते ही एक चीतल की गरदन बिना आवाज उसके जबड़ों में फंसकर शांत हो गयी। वन्य जीवों में भगदड़ मच गयी, लेकिन बाघ के जबड़ों से चीतल आजाद न हो सका। हमारे वाहन से बीस फुट दूर हुए इस शिकार के हम चित्र लेते रहे, पर जंगल के राजा को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। सौ किलो वजन के शिकार को मुंह में दबाये वह घनी झाड़ियों के बीच ऐसी मदमाती चाल से जा रहा था, जैसे चीतल नहीं खरगोश ले जा रहा हो। अभी वह बाघ अपने शिकार को मुंह में दबाये बमुश्किल पचास कदम चला होगा कि अचानक उससे दुगने आकार का एक और बाघ झाड़ियों से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिलीं। गुर्राहट हुई और बड़े बाघ ने छोटे बाघ से शिकार छीनने के लिए झपट्टा मारा। छोटे बाघ ने वह आघात तो अपने पांवों से रोक लिया, लेकिन शिकार छोड़कर दूसरी ओर चल दिया। बड़ा बाघ आधा मिनट उसे जाते तक देखता रहा, फिर शिकार को मुंह में दबा घनी झाड़ियों के बीच घुस गया।

रणथम्भौर के बाघ नरभक्षी नहीं हैं और न ही वे आदमी को देखकर भड़कते हैं। जयपुर के रियासती जमाने में माहौल दूसरा था। तब जयपुर के महाराजा अपने अंग्रेज मेहमानों को बाघ के शिकार की दावत दिया करते थे। उस वक्त जयपुर ही नहीं, पूरे देश में बाघ का शिकार व्यक्ति के रुतबे का प्रतीक माना जाता था। रियासतों के राजा-महाराजा, सामंत और अंग्रेज हाकिम जंगल की इस शान को कत्ल करके अपने घरों को सजाते थे। अखिल भारतीय शिकार रिकार्ड बताते हैं कि १९३८-३९ में उस समय के अंग्रेज वायसराय ने नेपाल की चितवान घाटी में दस दिनों में १२० बाघों का शिकार किया था। उदयपुर के महाराजा ने उस वक्त तक एक हजार बाघ मार डाले थे और सरगुजा के महाराजा ने तो ग्यारह सौ बाघ मारकर कीर्तिमान स्थापित किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस सदी के प्रारंभ में भारत में जहां ४० हजार बाघ थे, वहीं १९७२ में सरकारी गणना के अनुसार इन बाघों की संख्या १८२७ रह गयी। उसी वर्ष बाघों की रक्षा के लिए भारत में नौ क्षेत्रों को बाघ परियोजना के तहत विकसित किया गया। इनमें रणथम्भौर अभयारण्य को १९७४ में शामिल किया गया। इन अभयारण्यों में बाघों की रक्षा होने लगी और बाघों के लिए मनुष्य बाघभक्षी नहीं रहा।

रणथम्भौर अभयारण्य में ही दस सालों में बाघों की संख्या १४ से बढ़कर चालीस हो गयी। बीस वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बाघ की संतानें आज के आदमी को जीप में बैठकर उसकी गतिविधियां देखनेवाला दर्शकभर मानती हैं। जो बाघ पहले केवल रात में शिकार करता और दिन में छिपा रहता था, अब वह दिन के उजाले में शिकार करता है और बेधड़क घूमता है। इतने विशाल अभयारण्य में बाघ के दर्शन किस जगह हो सकते हैं? इस संबंध में बाघ परियोजना के प्रतिनिधि बतलाते हैं कि जहां गिद्ध मंडराते हों, सांभर पूंछ खड़ी करके बेतहाशा दौड़ता नजर आता हो, चीतल की अजीब-सी आवाज सुनायी देती हो, बंदर भयभीत हो पेड़ों पर चढ़े हों और पक्षियों के झुण्ड-के-झुण्ड कोलाहल के साथ अचानक उड़ते नजर आयें, तो समझ लेना चाहिए कि आसपास ही कहीं बाघ होगा। उस वक्त बाघ परियोजना के अधिकारी की यह हिदायत ध्यान में रखनी जरूरी हो जाती है कि आप जीप से न उतरें, खामोश रहें और धूम्रपान न करें।

छाया : [illegible]

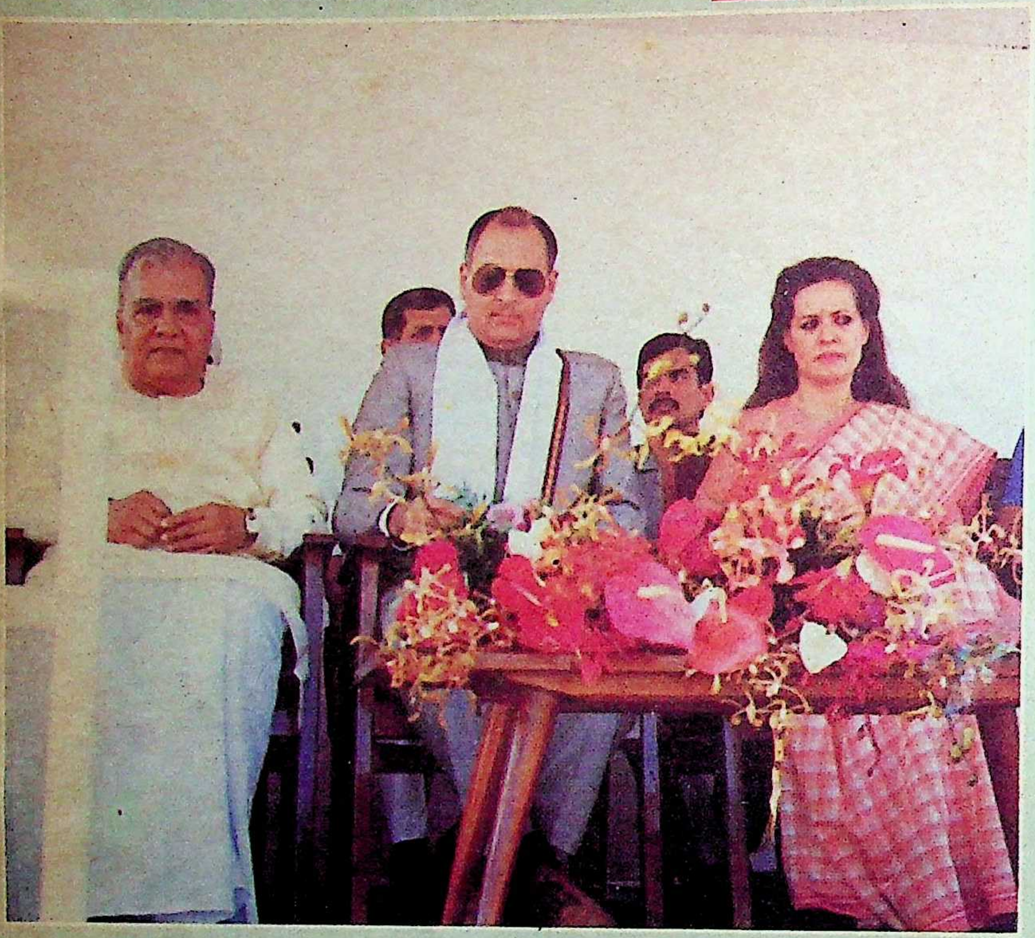

इस बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्षांत की छुट्टियां दूरदराज लक्षद्वीप में मनायीं। वहां उनके परिवार के अतिरिक्त उनके 'खास' रिश्तेदार और दोस्त भी थे, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। प्रधानमंत्री के इस तरह छुट्टी मनाने की यों तो कई तरह से आलोचना हुई है, लेकिन फिजूलखर्ची और सरकारी साधनों के दुरुपयोग की ज्यादा चर्चा हुई है। पर इन चर्चाओं से भी ऊपर चर्चा का विषय बना राजीव गांधी द्वारा 'व्हेलोद्धार'। (चित्र : श्रीमती सोनिया गांधी के साथ नौका विहार करते और स्थानीय समारोह में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री)

छाया : नितिन पोपट

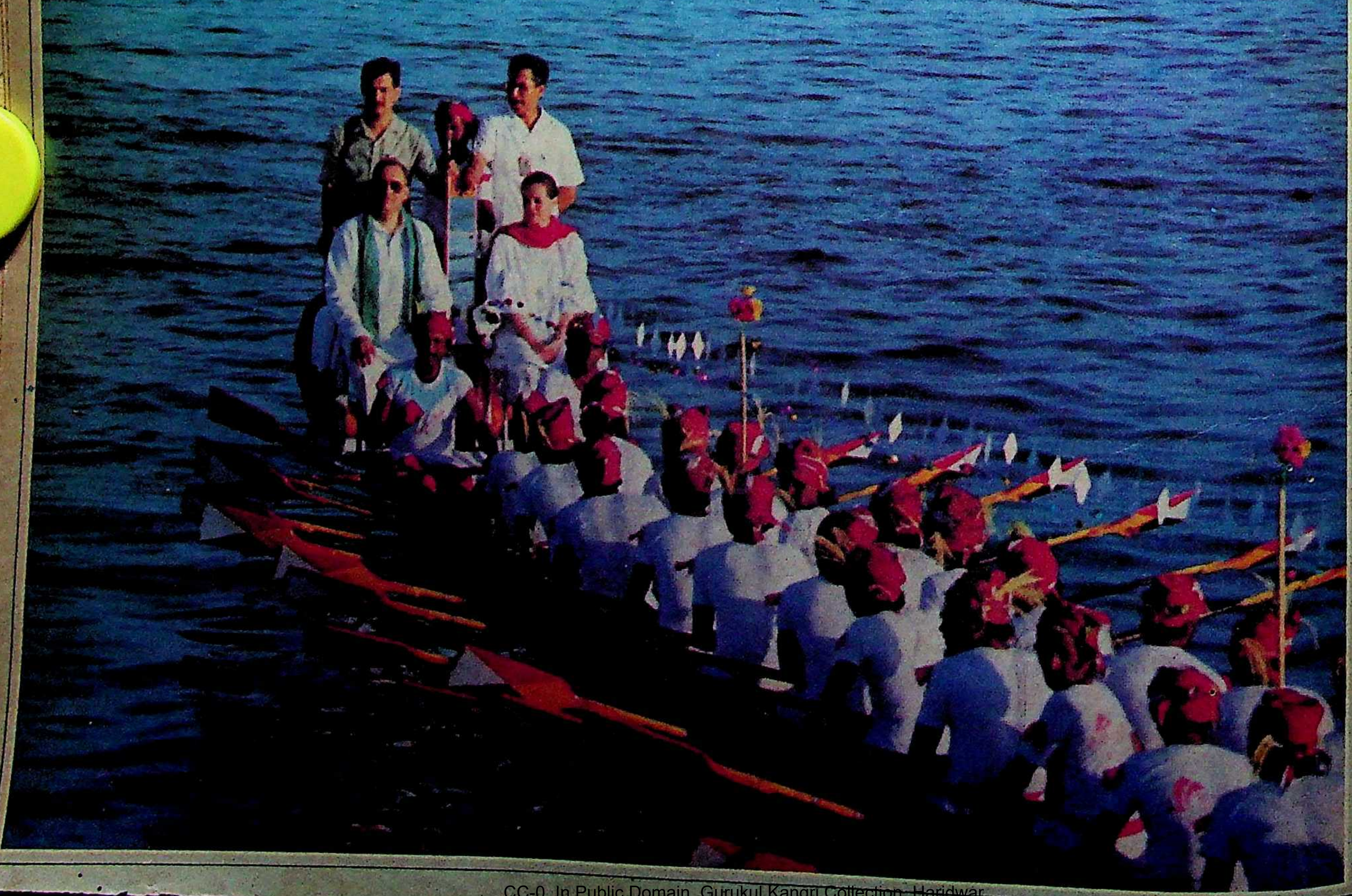

चोरी की कूटनीति

कहते हैं ज्ञानार्जन के लिए किताबें कैसे भी जुगाड़ी जा सकती हैं। अंग्रेजी में तो प्रसिद्ध ही हैं 'बेग, बारो आर स्टील' यानी भीख मांगकर, उधार लेकर या चोरीकर—किसी भी तरह किताबें हासिल कर लेनी चाहिए। इसके लिए क्या निर्धन, क्या धनवान—सभी के लिए यह अपराध क्षम्य है। वैसे तो चोरी करना सामाजिक दृष्टि से पाप और न्यायिक दृष्टि से अपराध है, चाहे वह राजा करे या रंक। यदि कोई दरिद्र हाथ की सफाई दिखाये, तो समझ में आता है, लेकिन कोई ओहदेदार ऐसा करे, तो ताज्जुब तो होगा ही। हुआ यों कि अमरीका स्थित नेपाली राजदूत विश्व प्रधान द्वारा क्रिसमस की पूर्व संध्या में किताबों की एक दूकान से आयुर्विज्ञान संबंधी किताबों के चुराने का मामला प्रकाश में आया। लेकिन प्रधान साहब का कहना है कि पाकिस्तान में पढ़ रही अपनी पुत्री के लिए वह किताबें खरीदना चाहते थे। वह यह किताबें लेकर यह देखने के लिए बाहर निकले थे कि क्या वही किताबें उनकी बेटी ने मंगायी हैं। उनके बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें टोका। लेकिन उनके राजनयिक पासपोर्ट देख लेने पर पुलिस शांत हो गयी और वह चले गये। पर नेपाल सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

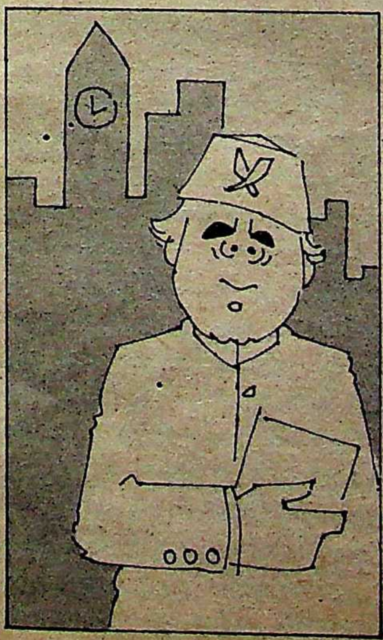

जानवरों की जन्म कुंडली

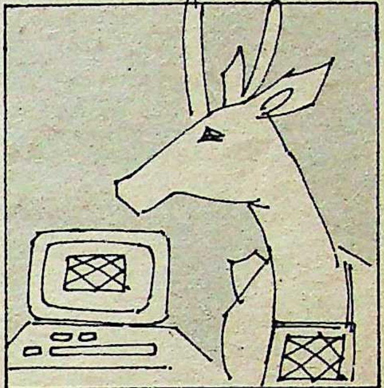

"एक सुघड़-सुंदर, इकहरे बदन वाली,घरेलू कार्यों में दक्ष १६ वर्षीया कन्या की आवश्यकता है जो चिट्ठी-पत्री लिख लेती हो तथा खाना बनाने और सिलाई-कढ़ाई में भी निपुण हो," जैसा वैवाहिक विज्ञापन तो पत्र-पत्रिकाओं में अकसर पढ़ने को मिल जाता है। यही नहीं, अब तो कंप्यूटर से भावी वर-वधू की कुंडली भी मिलायी जाती है तथा उनके आजीवन कुशलता की कामना की भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन अब जानवरों के परिणय-सूत्र में बंधने के लिए भी कंप्यूटर की ईजाद हो गयी है। यों सामंती तबका तो अपने कुत्तों का बर्थ-डे मनाता ही है और उनकी शादियां भी करता रहा है, लेकिन अब सरकार के संस्थान भी जानवरों के हितचिंतक और नस्ल सुधारू हो गये हैं। दरअसल दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणि उद्यान के निदेशक कमल नायडू ने देश के सभी चिड़ियाघरों से चीते, बाघ, भालू, हिरन तथा बंदरों आदि के लिए फार्म भेजकर नर और मादा दोनों की जानकारी चाही है। आवश्यक जानकारियों में उन्होंने दोनों के लिंग, उम्र, वजन आदि का ब्योरा मांगा है। इन ब्योरों का मिलान शादी करानेवाले पंडितजी पत्रे से नहीं करेंगे, बल्कि नायडू साहब उनको कंप्यूटरों में डालकर दिखवायेंगे कि किन-किन जानवरों की लग्न-पत्री मिलती है। अब देखना है कि कितने प्रस्ताव आते हैं। सही भी है, २१ वीं सदी में मनुष्यों के साथ जानवरों को भी तो जाना है, इसलिए कंप्यूटर से उनकी शादियां भी होनी ही चाहिए।

मि० भंगेड़ी

भंग का रंग भी क्या खूब होता है कि उसकी तरंग में आकर लोग बड़े-बड़े काम कर डालते हैं। सरकार चाहे भले ही नशे पर पाबंदी लगाती रही हो या मोरारजी भाई जैसे महान पुरुष शिवांबु के पक्षधर रहे हों, लेकिन शंकर के गणों को कोई रोक नहीं सकता। 'भारत मित्र' के प्रातःस्मरणीय संपादक बाबू बालमुकुंद गुप्त ने तो लार्ड कर्जन तथा गोरी चमड़ीवालों की खबर लेने के लिए 'शिवशम्भु के चिट्ठे' तक लिख डाले। गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' के शिष्यों ने तो 'हालावाद' की तर्ज पर भंग को केंद्र में रखकर 'विजयावाद' जैसा आंदोलन ही चला दिया। फिल्म 'डान' में भंग का रंग अमिताभ बच्चन के ऊपर ऐसा चढ़ा कि हर किशोर के मुंह पर वह गाना चढ़ गया था। होली में तो हर कोई भंग के रंग में रंगा रहता है और यदि सच्चे भंगेड़ी देखना हो, तो इस मौके पर बनारस चले जाइए। लेकिन फिलहाल बनारस नहीं मथुरा में एक ऐसा हंगामा हो गया कि उसकी चर्चा हो गयी। वहां विश्राम घाट पर भांग पीने की दिलचस्प प्रतियोगिता आयोजित हुई। यों तो लोग चुटकी लेते हैं कि चौबेजी गये छब्बे बनने, लेकिन इस बार चौबेजी ने कमाल ही कर दिया। इस प्रतियोगिता में मथुरा नगरपालिका के एक चौबेजी ने ८०० ग्राम भंग पीकर प्रथम पुरस्कार हासिल किया और हरि चौबे ३०० ग्राम भंग पीकर दूसरे स्थान पर रहे। इन विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, दुशाला और नकद पुरस्कार भी दिये गये।

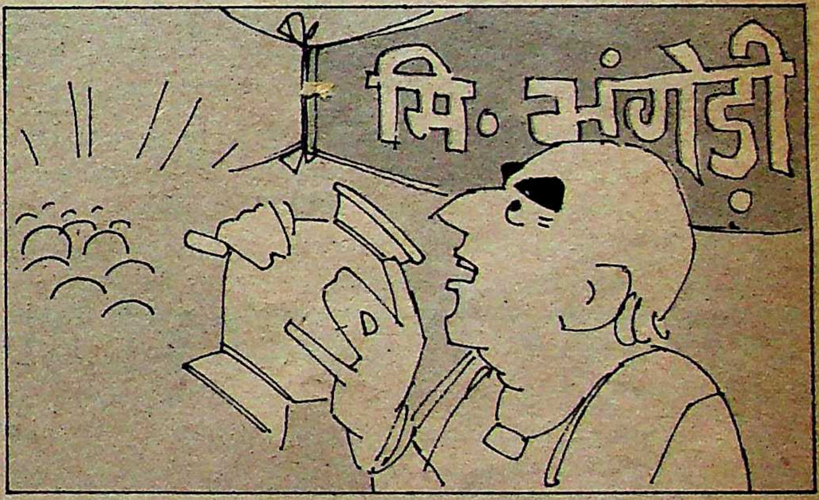

एक साड़ी, दो औरत

हम २१ वीं सदी की देहलीज पर खड़े हैं। कहने को तो हमारे विकास के लिए कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, कितने ही बीससूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रम बने। सरकार की दृष्टि में हम गरीबी रेखा से ऊपर भी उठ गये हैं, लेकिन बांसवाड़ा जिले के आदिवासी गांवों में आज भी यशपाल की 'परदा' कहानी चरितार्थ होती है। वहां आज भी ऐसे परिवार हैं जहां साड़ियों के अभाव में औरतों को नंगा रहना पड़ता है। खाने-पीने की चीजें तो उन ग्रामवासियों के लिए मुहैया कराना कपोल-कल्पना है ही, फटेहाली का यह आलम है कि सास-बहू दोनों के पास एक ही फटी साड़ी होती है। जब सास बाहर जाती है, तो बहू घर में नंगी रहती है और जब बहू बाहर जाती है, तो सास घर में नंगी रहती है।

—संयोजन : कु० [illegible]

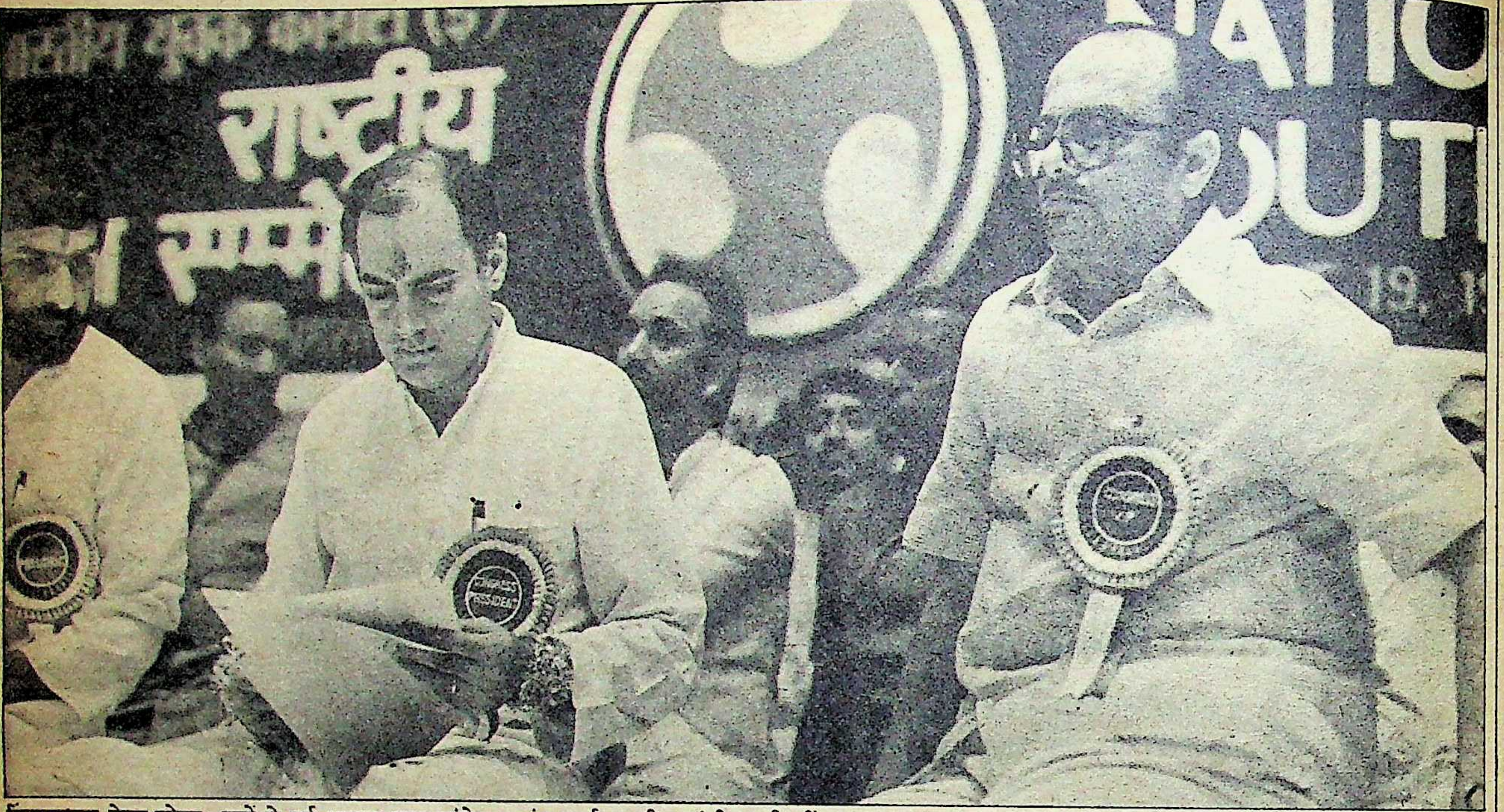

चिंताजनक लेखा-जोखा: बायें से पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस आनंद शर्मा, राजीव गांधी, अर्जुन सिंह

इंका संगठन

क्या फिर से जिंदा हो पायेगा ?

"ऐसा नहीं है कि आज का कांग्रेसी कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं। वह कुछ करना चाहता है। किंतु उसे कांग्रेस के उसूलों के लिए काम करने का मौका नहीं दिया जाता। हम उसे वह मौका दे रहे हैं। यह कारगर साबित हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगले पांच वर्षों में कांग्रेस बेहद मजबूत हो जायेगी।"

राजीव गांधी, १९८५ में प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद।

लेकिन तीन साल के अंदर— १९८८ तक उजागर सचाई उसके उलट साबित हुई। इस काल में पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, असम व केरल जैसे राज्यों में पार्टी के हाथों से सत्ता छिन गयी। इसे अत्यधिक प्रभावशाली पार्टी सहयोगियों के हाल के वर्षों के जबरदस्त अंतर्पार्टी विद्रोह का साक्षी होना पड़ा, जिसका नेतृत्व पूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कर रहे थे, जिनका 'जनमोर्चा' अब हिंदी हृदय प्रदेश में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और 'आंतरिक लोकतंत्र' के युग के सूत्रपात के लिए पार्टी चुनावों का बार-बार किया गया वायदा लगातार टाला जाता रहा है। गलती कहां हुई ? राजीव गांधी आज अत्यधिक जटिल चक्रव्यूह में क्यों फंस गये हैं ? आम चुनावों के लिए दो वर्ष से कम का समय बचा है और स्थिति यह है कि कांग्रेस की बिगड़ती छवि को मांजने-चमकाने के अभियान के बारे में प्रधानमंत्री सरिस्का (राजस्थान) में अनौपचारिक कैबिनेट मीटिंग ही कर रहे हैं। क्या इस पर सचमुच अमल होगा ? होगा भी, तो क्या कामयाबी मिलेगी ?

अपनी मां इंदिरा गांधी की बर्बर हत्या के फौरन बाद अक्तूबर १९८४ में पार्टी और देश की बागडोर संभालते वक्त राजीव गांधी ने लोकमोहक वायदे किये थे। अपने शासन के शुरुआती दिनों में उन्होंने उन पर अमल भी किया था। प्रमुख विपक्षी नेता व जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर तक ने तब माना था, "मेरे अनेक पार्टी सहयोगी राजीव की शैली से हतप्रभ थें। उन्हें उनकी कोई बड़ी गलती ढूंढ़े नहीं मिलती थी।" उस समय श्री गांधी मात्र सरकार के कामकाज के लिए चिंतित नहीं, अपनी पार्टी में सुधार के लिए भी कटिबद्ध नजर आते थे।

छवि में अंतर: १९८५ में बंबई में कांग्रेस शताब्दी समारोह में श्री गांधी ने अपनी पार्टी के लोगों को कठघरे में खड़ा करते हुए आक्रामक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, "वे अपना उल्लू सीधा करने वालों की ऐसी टोली हैं जो जातिवाद के नारे पर फलफूल रहे हैं और अपनी धनपिपासा के जाल में कांग्रेस संगठन का सर्वनाश कर रहे हैं।" उनके लिए, "जनता का कोई महत्व नहीं। उनकी जीवन शैली, उनकी विचारधारा, उनकी स्वार्थलिप्सा, उनके भ्रष्ट तरीके, उनकी समाज के निहित स्वार्थों से साठगांठ और उनका पाखंडपूर्ण रवैया जनता के बीच काम करने के कतई लायक नहीं। वें कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे खोल में बदल रहें हैं, जिसके भीतर से सेवा और त्याग की भावना तिरोहित हो गयी है।" ये कड़े शब्द हैं, "किंतु सचाई कड़वी होती है," पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री व सांसद वी०एन० गाडगिल कहते हैं। "बहरहाल, राजीव गांधी जो कुछ बोलते हैं, वही वह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं," यह बात एक कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस

जोड़तोड़ की राजनीति: सांसद एच०के०एल० भगत राजीव गांधी से गुफ्तगू करते हुए

अध्यक्ष जोर देकर कहते हैं। आज तो लोग उनकी इस आदत से खूब वाकिफ हो गये हैं, किंतु उस समय उनकी ऐसी छवि नहीं थी, जब वह कांग्रेस महासचिव (१९८३-८४) थे। उस दौरान उनकी कथनी-करनी में साम्य था। उन्होंने अपने दिवंगत भाई की तड़क-भड़क युक्त 'संजय वाहिनियों' (ब्रिगेडों) के लोगों मसलन प्रणब मुखर्जी, गुंडूराव, ए०आर० अंतुले, आर०के० धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पार्टी में हाशिए पर डाल दिया था। 'संजयवाद विरोधी' इस मुहिम के साथ-साथ वह अपना गुट तैयार कर रहे थे, जिसमें अरुण नेहरू, सिद्धार्थ रेड्डी व विजयधर शामिल थे। इनमें से अधिकांश श्री गांधी के दून स्कूल के दोस्त थे तथा राजनीति में नये-नये आये थे, इसलिए उनकी बेदाग छवि थी। दरअसल उस समय पार्टी हल्के में यह कहावत मशहूर थी, "गून्स (गुंडों) की जगह दून्स (दून स्कूल वाले) काबिज हो रहे हैं।"

इन 'युवाओं' की कार्यविधि पहले की कांग्रेस से स्पष्टतः अलग है और यह एक नयी व्यवस्था के पोषक, अनुशासनबद्ध और परिश्रमी लोग हैं ऐसा दिसंबर १९८३ में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन में प्रकट हुआ था। चार दिन के अल्प समय में राजीव गांधी ने १७ कांग्रेस मुख्यमंत्रियों, २२ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों व इतनी ही तादाद में युवा कांग्रेस अध्यक्षों, राष्ट्रीय छात्र यूनियन (एन एस यू आई), सेवादल के प्रदेशाध्यक्षों, महिला, अल्पसंख्यक व विधि प्रकोष्ठों, श्रम मोर्चे के मुख्य पदाधिकारियों से भेंट की। श्री गांधी के ममेरे भाई और मौजूदा विद्रोही जनमोर्चा सांसद अरुण नेहरू उन दिनों का स्मरण करते हैं, "राजीव और मैं पूरे समय पार्टी के काम में लगे रहते। हमें समूचे देश के प्रमुख पार्टीजनों का परिचय मिल गया था।"

नयी शैली: तब राजीव गांधी कांग्रेस को १९८५ के आम चुनावों के लिए तैयार कर रहे थे। उनके कार्यों से ऐसी धारणा बनी थी कि वह पार्टी को गंभीरतापूर्वक समझना चाहते हैं। उसकी कमजोरियों को जान-समझ उन्हें दूर करना चाहते हैं। यह जानने के लिए कि पार्टी-सांसदों और विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी जानकारी है, प्रश्नावलियों की एक प्रणाली और साक्षात्कारों को लागू किया गया। मार्च १९८४ में नयी दिल्ली में तीन दिन का एक अधिवेशन आयोजित करके मुख्यमंत्रियों, ३६० सांसदों, ३००० विधायकों से विस्तृत साक्षात्कार किये गये। इसमें प्रयुक्त प्रश्नावलियों से व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ अगले चुनाव में पार्टी की संभावना का जायजा लिया गया। मजेदार बात यह है कि उनका (राजीव) खुद का साक्षात्कार पी० शिवशंकर (जो अब उनके कैबिनेट सहयोगी हैं) ने अमेठी में पार्टी की संभावना के बारे में लिया तथा इंदिरा गांधी का साक्षात्कार प्रणब मुखर्जी ने लिया।

पार्टी की परंपराओं को ताक पर रखते हुए 'कंप्यूटरजी', (तब राजीव गांधी इसी नाम से पुकारे जाते थे) ने 'आधुनिक प्रबंधन तकनीकों' को अपनाया। तथ्यों और आंकड़ों के प्रति उनकी दिलचस्पी का यह आलम था कि २४-अकबर रोड, दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में तालिकाओं और मानचित्रों की भरमार थी। वहां विभिन्न जिलों के ऐसे नक्शे भी थे, जिनमें कांग्रेसी और विपक्षी दलों के प्रभाव क्षेत्रों को दिखाया गया था। अखबारों की कतरनें, राज्यों के अधिकारियों के पत्र-व्यवहार और पार्टी अधिकारियों के दौरों के रिकार्ड भी करीने से रखे जाते थे। इस संबंध में भारत के प्रख्यात राजनीति वैज्ञानिक रजनी कोठारी कहते हैं, "तपे-तपाये पार्टी राजनीतिज्ञों के स्थान तकनीक विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेटों) और गांधी परिवार के पिछलग्गुओं ने हथिया लिये।"

राजीव गांधी ने अपने इर्द-गिर्द भूतपूर्व राजाओं, पूर्व व्यावसायिक प्रबंधकों की एक अंतरंग टोली बना ली थी जो पब्लिक स्कूल के अपने परिवेश-प्रभाव से कंप्यूटरों, नूतन तकनीक और आधुनिक प्रबंधन की बातें करते थे और जिन्हें व्यंग्य से पुरानी परंपरा के कांग्रेसी 'बाबा लोग' (अभिजात परिवार के बच्चे, जिनकी परवरिश नौकर-चाकर करते हैं) कहते थे। ये तमाम गैर-राजनीतिक अभिनेता कांग्रेस पर जबरन थोप दिये गये थे, जिनका पार्टी में कोई समर्थन अथवा आधार नहीं था। ये एक 'विशिष्ट क्लब' की शक्ल में बने हुए थे। इनका गांधी पर एकाधिकार था और उन्होंने उनको दूसरों की पहुंच से दूर कर दिया था। किंतु ये पार्टी में अपनी हैसियत और स्थान अर्जित करने में अक्षम थे और कांग्रेस में बेगाना होने के कारण उसकी प्रकृति से अनभिज्ञ थे। इसलिए इन कंप्यूटर छोकरों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने मन से स्वीकार नहीं किया। इस स्वीकृति के लिए प्रयास करने के बजाय इन्होंने कार्यकर्ताओं को क्रुद्ध, कुंठित, असंतुष्ट और अलग-थलग कर दिया।

श्री गाडगिल कहते हैं, "पहले कांग्रेस में वर्षों सक्रिय कार्यकर्ता होने वाले को ही संसद या विधानसभा का टिकट मिलता था। किंतु गत कुछ

तदर्थवाद का लाइलाज रोग

कुछ समय पहले तक कांग्रेस के महासचिव रह चुके एक वरिष्ठ सांसद का कहना है, "कांग्रेसियों की संख्या लाखों में है, मगर उनमें संगठन नाम की चीज नहीं है।" मतलब साफ है। आज के कांग्रेसी दिशाहीन हैं। एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के शब्दों में, "इन दिनों हालत यह है कि कांग्रेसियों के बायें हाथ को भी नहीं मालूम कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है?" यह दिशाहीनता कांग्रेस में हर तरफ व्याप्त है, पर कोई नहीं जानता, इसे दूर कैसे किया जाये?

कांग्रेस के शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह घोषणा करके अपने भाषण को यादगार बना दिया था कि वह पार्टी को 'सत्ता के दलालों' से मुक्त करेंगे। राजीव ने यह भी वादा किया था कि वह पार्टी के सभी सदस्यों के अतीत और उपयोगिता की जांच करायेंगे। अतः १९७२ से स्थगित संगठन के चुनाव कराये जाने की संभावना भी बढी। राजीव गांधी ने जनवरी '८६ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की अध्यक्षता में 'सांगठनिक चुनाव देखरेख समिति' का गठन किया। बहरहाल, उनकी रिपोर्ट अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। किसी को भी नहीं मालूम कि उस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिये गये थे।

अप्रैल १९८६ में बुजुर्ग कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी ने अपने बहुचर्चित और विवादास्पद पत्र के जरिये पार्टी में बोगस सदस्यता की शिकायत राजीव गांधी से की थी। इस पत्र के कारण पूरे साल सनसनी फैली रही और पार्टी नेतृत्व एक अभूतपूर्व संकट से भी घिरा रहा। फरवरी १९८७ में श्री गांधी ने बुजुर्ग नेता उमाशंकर दीक्षित को दस सदस्यीय 'सांगठनिक चुनाव जांच समिति' का अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक पुनर्जीवन प्रदान किया। चार माह बाद, जब समिति किसी निष्कर्ष तक पहुंची भी नहीं थी कि राजीव गांधी ने आश्चर्यजनक रूप से श्री दीक्षित को उठाकर 'संगठन के मामलों' की समिति का अध्यक्ष बना दिया। उनसे पार्टी के संगठन को हर स्तर पर सक्रिय करने और जनवरी १९८८ तक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रक्रिया और कार्यक्रम संबंधी सलाह मांगी गयी।

त्रिपाठीजी का अड़ंगा : कहा जाता है कि श्री दीक्षित ने गत दिसंबर में पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उन्होंने कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तनों और जून '८८ तक संगठन के चुनाव कराने की सिफारिश की थी। बहरहाल, २६ दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उक्त सिफारिशों पर विचार करके भावी कदम उठाने के बारे में निर्णय लिया जाना था, मगर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। कमलापति त्रिपाठी जैसे कुछ बुजुर्ग नेताओं के अलवा कोई इन सिफारिशों से सहमत नहीं था। जाहिर है इससे दीक्षितजी को निराशा हुई होगी, मगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने 'माया' से कहा, "यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि 'पार्टी फोरम' के अलावा कहीं और इस पर चर्चा करूं। इस मुद्दे को इस समय सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी इस पर पार्टी स्तर पर विचार किया जा रहा है।"

> इन दिनों हालत यह है कि कांग्रेसियों के बायें हाथ को भी नहीं मालूम कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है? यह दिशाहीनता कांग्रेस में हर तरफ व्याप्त है, पर कोई नहीं जानता, इसे दूर कैसे किया जाये?

हालांकि सांगठिक चुनावों का कोई खुला विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी बतायी जाती है जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत करने की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। पार्टी के एक पूर्व महासचिव और केन्द्रीय मंत्री का कहना है, "ये लोग पार्टी के संविधान की अवहेलना करके भी इस व्यवस्था को चालू रखना चाहेंगे। १९७७ के बाद जिला स्तर से लेकर कांग्रेस कार्य समिति तक सभी पदाधिकारी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि १० से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस समितियों (पी०सी०सी०) के सदस्य भी नहीं हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के कुछ महासचिव कार्यकारिणी समिति (ए०आई०सी०सी०) के सदस्य तक नहीं हैं।"

१९७२ के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक यही हालत राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है। यह तदर्थवाद उड़ीसा और गोवा में १९६८ से तथा गुजरात में १९७४ से चला आ रहा है। जम्मू और कश्मीर की निर्वाचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी को १९७५ में भंग करके एक तदर्थ समिति बनायी गयी थी जो अब भी बरकरार है।

बहरहाल, संगठन के चुनावों की संभावना तब तक दिखलायी नहीं पड़ती, जब तक कि पार्टी सदस्यों की विवादास्पद भरती का मामला हल नहीं हो जाता। पार्टी के संविधान के अनुसार 'सक्रिय सदस्य' ही पदाधिकारी बन सकते हैं। सक्रिय सदस्य का दर्जा उस प्रारंभिक सदस्य (प्रारंभिक सदस्य कोई भी १८ साल से ऊपर का व्यक्ति बन सकता है जो पार्टी के संविधान में विश्वास रखता हो और एक रुपया द्विवार्षिक शुल्क अदा करता हो) को मिलता है, जिसकी उम्र २१ वर्ष से ऊपर हो और जो या तो द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में २५ रुपए दे या २५ लोगों को प्रारंभिक सदस्य बनवाये।

मौजूदा हालत : कांग्रेस संगठन की मौजूदा हालत १९६९ के विघटन के बाद हुई है। पार्टी की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करने के लिए केवल २५ लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाने की जरूरत होती है, लेकिन इसी नियम के कारण ढेरों समस्याएं खड़ी हुईं। इससे तथाकथित बोगस सदस्यता के लिए रास्ते खुल गये। स्वार्थी लोगों ने अपने समर्थकों को सक्रिय सदस्य बना दिया और संभावित चुनावों में अपनी स्थिति विजेता की-सी बना ली तथा पार्टी में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वैसे बोगस सदस्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले श्री त्रिपाठी की ही इसके लिए सबसे ज्यादा खिंचाई हुई है। उनके विरोधियों ने आरोप लगाया था कि सबसे ज्यादा बोगस सदस्यता उनके शहर बनारस में ही दी गयी है।

सूत्रों के अनुसार इस समस्या पर विचार करने के बाद श्री दीक्षित ने एक रास्ता सुझाया था। उनकी योजना के अनुसार कांग्रेस-इ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, इंका सांसद और विधायक तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने-अपने चुनाव क्षेत्र से १५-१५ सक्रिय सदस्यों की सूचियां तैयार करेंगे। इसके बाद पार्टी हाईकमान इन सूचियों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। पार्टी की विभिन्न कार्यसमितियों की सहायता से इन सूचियों की जांच की जायेगी। इससे उनकी विश्वसनीयता की परख भी हो जायेगी। दूसरे चरण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेक्षक प्रदेशों की राजधानियों में जायेंगे, जहां ब्लाक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुने जायेंगे। चुनाव अनिवार्य रूप से सर्वसम्मति के आधार पर होंगे। निचले स्तर की कमेटियों के उक्त ढंग से मनोनयन के बाद केन्द्रीय पदाधिकारियों का चुनाव विभिन्न समितियों के आपसी विचार-विमर्श से होगा। अंतिम चरण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा।

बहरहाल, श्री दीक्षित की इन सिफारिशों पर राजनीतिक प्रेक्षकों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। 'स्टेट्समैन' के अनुसार, "कांग्रेस नेतृत्व 'शार्ट कट' अपनाने की सोच रहा है, लेकिन यह तरीका संगठन को शक्तिशाली बना पायेगा इसमें संदेह है।" और इस मत से लगभग सभी सहमत हैं।

—प्रकाश नंदा

केवल कागजों पर: सेवादल की एक बैठक का दृश्य

वर्षों से यह परंपरा ताक पर रख दी गयी। आज कोई पार्टी में शामिल होता है, कल वह सांसद बन जाता है। फिर एक दिन बाद मंत्री। पार्टी ऐसे पुनर्गठित और व्यवस्थित नहीं की जा सकती।"

भारत जैसे देश में राजनीति पर जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र का निर्णायक प्रभाव है। इस सचाई को नजरंदाज कर "प्रबंधकीय रवैया राजनीति पर हावी हो, तो उसकी विफलता अवश्यंभावी है," श्री गाडगिल का मत है। और यही मुद्दा आगे चलकर तब उजागर हुआ, जब यह समझ में नहीं आ रहा था कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी और उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह, जिन्हें श्री गांधी ने जुलाई १९८६ के आरंभ में पार्टी को पुनर्गठित करने और शीघ्र पार्टी चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया था, के बीच छिड़े सत्ता संघर्ष का कैसे सामना किया जाये (देखें बाक्स)। श्री त्रिपाठी और श्री सिंह—इन दोनों के पदों की पार्टी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं थी तथा दोनों क्रमशः ब्राह्मण और ठाकुर लाबियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस युद्ध में श्री सिंह विजयी हुए थे और श्री त्रिपाठी की प्रतिक्रिया अब इतिहास का एक भाग बन चुकी है। यद्यपि कांग्रेस के इस दिग्गज वयोवृद्ध हस्ती को अभी भी पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी में स्थान प्राप्त है और वह कभी-कभार अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं, किन्तु श्री सिंह ने उनकी राज्यसभा में पुनः नामजदगी में रोड़ा अटकाकर उनको लुंजपुंज कर दिया है। अर्जुन सिंह को बाद में पार्टी पद से हटाकर राजीव गांधी मंत्रिमंडल का एक सदस्य बना दिया गया। "किंतु तब तक वह कांग्रेस को अनगिनत हानि पहुंचा चुके थे," ऐसा शासक पार्टी के एक सांसद मानते हैं।

नरेशचंद्र चतुर्वेदी

श्री गांधी की पार्टी-ढांचे में बार-बार परिवर्तन करने के लिए आलोचना की जाती रही है। पिछले तीन वर्षों में तीन बार अज्ञात कारणों से महासचिवों को बदला गया।

वह बड़ी चालाकी व कुशलता से राजीव गांधी को अलग-थलग कर स्वयं पार्टी अध्यक्ष और सामान्य कार्यकर्ताओं के मध्य महत्वपूर्ण सेतु बन गये थे। पार्टी महासचिवों तक को अपने मतभेदों व विरोध की बात उनके कानों में डालनी पड़ती थी। इस प्रकार २४-अकबर रोड में पार्टी नेताओं के मध्य तालमेल व समन्वय का कोई तरीका नहीं बचा था। "यह रोग अभी भी बरकरार है, जिसका इलाज होना बाकी है," एक पूर्व पार्टी महासचिव कहते हैं, "दरअसल हमारे पास मिल-बैठकर बात करने और मसला हल करने का समय तक नहीं है।"

श्री गांधी की पार्टी-ढांचे में बार-बार परिवर्तन करने के लिए आलोचना की जाती रही है। पिछले तीन वर्षों में तीन बार अज्ञात कारणों से महासचिवों को बदला गया। केवल एक महासचिव जी०के० मूपनार इस रद्दोबदल की लपेट से बचे रहे। बहरहाल, ताजातरीन टीम, खासकर इसके चंद सदस्यों की क्षमता को लेकर पार्टी के कुछ हल्कों में तीखी आलोचना हुई। "गत दो महीनों में इन महासचिवों ने, अनेक मुद्दों पर कई बार, एक-दूसरे के बयानों का खंडन किया। इससे यह समझना बड़ा कठिन है कि पार्टी का पक्ष क्या है," ऐसा एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री कहते हैं।

कुछ पार्टी सांसदों ने, जिन्होंने पार्टी को सांसत में डालने वाले विवादग्रस्त मसलों पर टिप्पणी की थी, मामले को और 'बदतर' बना दिया। जनमोर्चा सांसद अरुण नेहरू कहते हैं, "मैं चाहता हूं कि राजीव अपने सिपहसालारों-मसलन कल्पनाथ राय, के०के० तिवारी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और जगदीश टाइटलर के साथ अपना 'काम' करते रहें। इस स्तर के कांग्रेसियों के होते हुए हमें श्री गांधी से संघर्ष करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुदबखुद हमारे पास आयेंगे।"

प्रख्यात पत्रकार गिरिलाल जैन के अनुसार, "राजीव गांधी के इर्द-गिर्द एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे किसी भी तरह कूटनीतिक चिंतक कहा जा सके, जो व्यापक संदर्भ में सोच-समझ सके और एक ऐसा साहसिक कार्यक्रम तय कर सके, जिससे कांग्रेस पार्टी को १९८९ के बाद शासन करने का पुनः जनादेश प्राप्त हो सके।" यह एक तीखा कथन है, किंतु श्री गांधी के कुछ अपने पार्टीजन भी इस तरह से सोच रहे हैं। "ठोस सलाह देने वालों की कांग्रेस में कमी नहीं है, किंतु राजीवजी की इसमें दिलचस्पी नहीं है" यह कथन कांग्रेस कार्यकारिणी व संसदीय दल के एक सदस्य का है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति व कांग्रेस संसदीय दल जैसे मंचों को प्रायः ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में अंधेरे में रखा जाता है। "हालत तो यह है कि उनकी सूचना हमें प्रातः अखबारों से मिलती है" यह रहस्योद्घाटन राजस्थान के एक वरिष्ठ कांग्रेस सांसद ने किया है।

प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद श्री गांधी ने

कांग्रेस संसदीय दल को निर्णायक भूमिका का आश्वासन दिया था। १९८५ में उन्होंने संसदीय दल की प्रत्येक मंत्रालय मे संबद्ध प्रवर समिति को पुनरुज्जीवित किया था। इन पैनलों को बनाने का अमली मकसद था—संबंधित मंत्रालयों द्वारा लिये जाने वाले किसी निर्णय के पूर्व उस पर व्यापक विचार-विमर्श। किंतु धीरे-धीरे वे मृतप्राय हो गयीं और संसद के अधिवेशन के दौरान यदा-कदा ही बैठकें हुई। मसलन सांसद चिमनभाई मेहता चाहते थे कि संसद में पेश होने वाले संभावित बिलों पर नेतृत्व द्वारा सदस्यों को ह्विप आदेश जारी करने के पूर्व कांग्रेस संसदीय दल की बैठके में विचार-विमर्श करना चाहिए। संसदीय दल की बैठक बुलायी गयी, पर सदस्यों के पहुंचने पर बताया गया कि बैठक 'स्थगित' कर दी गयी है। ऐसी घटनाओं से अत्यधिक क्षुब्ध सदस्यों ने अनेक पैनलों से अपना पल्ला झाड़ लिया।

वैसे 'पार्टी' में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और 'व्यक्ति पूजा' कांग्रेस के लिए कोई नयी बात नहीं। यह बात लोकसभा के १९६२ से सांसद रहे एक कांग्रेसी ने स्वीकार की, "मैं महज कांग्रेसी होने के नाते कभी नहीं चुना गया। लोगों ने मुझे हमेशा इस लिए वोट दिया, क्योंकि पहले मैं नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और अब राजीवजी के साथ हूं।" किंतु राजीव गांधी और उनकी मां व नाना में एक फर्क है। वे दोनों दिवंगत नेता 'वोट बटोरने' वाले थे। दूसरी ओर राजीव गांधी इस मामले में विफल साबित हुए हैं। अरुण नेहरू की टिप्पणी है, "औसत कांग्रेसी बड़ा चतुर है। वह हमेशा जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाता है और राजीव इस कोटि में नहीं आते।"

इधर कुछ महीनों से श्री गांधी पार्टी मामलों में अधिक रुचि ले रहे हैं। अनेक राज्यों के चुनावों में मिली पराजय के पश्चात अपनी मां के समान उन्होंने भी 'वामपंथी नारों' मसलन अस्थिरीकरण जैसे सिद्धांतों का आश्रय लिया है। गत दिसंबर में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में श्री गांधी ने भूमि सुधार, किसान समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, आवास समस्या, संप्रदायवाद और हरिजनों-आदिवासियों की कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने इन मसलों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए समितियों के गठन का आदेश दिया। समितियों की सिफारिशों पर पार्टी आलाकमान बाद में कार्रवाई करेगा। उनके सहयोगियों ने कांग्रेस को एक 'सुदृढ़ कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनाने' पर बल दिया।

घटता जनाधार: बहरहाल, कांग्रेस कभी कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि इसने 'आंदोलन' की भूमिका निभायी है। इसमें न केवल विभिन्न तथा परस्परविरोधी विचारधारा के लोग रहे हैं, बल्कि जनता का ऐसा व्यापक वर्ग भी इसमें रहा है जो सत्ता के दांवपेंच में संलग्न नहीं था। "यह एक जन संगठन है, जिस क्षण कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाने की बात सोची जायेगी, उसी समय विनाश का बीजारोपण हो जायेगा" ऐसा

युवा कांग्रेस

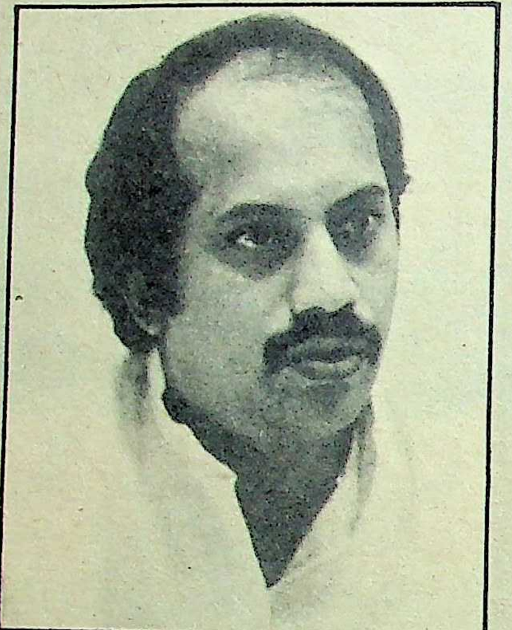

गुरुदास कामथ

नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुरुदास कामथ जब इस बात का खंडन करते हैं कि 'भारतीय युवा कांग्रेस केवल कागजी शेर है', तो वह पूरी बात कह देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन होने के बावजूद (जिसका दावा है कि उसके १० लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं) युवा कांग्रेस की उपलब्धियां नगण्य हैं। वास्तव में संगठन की छवि बहुत खराब है। आम तौर पर इसके सदस्यों को 'गुंडों' या 'बदमाशों' की तरह देखा जाता है। १९८४ में नागपुर और १९८५ में मास्को युवा महोत्सव में इनकी कारगुजारियों को इसी रूप में याद किया जाता है। मास्को में संगठन की भद्दी गतिविधियों के कारण सचिवालय से इस्तीफा दे देनेवाले कामथ दुखी मन से कहते हैं, "यह धारणा काफी व्यापक है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए।" वह कहते हैं, "मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अपने कार्यकाल में मैं आपराधिक गतिविधि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को संगठन में जगह नहीं दूंगा।"

जब संजय गांधी का कांग्रेस में वर्चस्व था तब क्या युवा कांग्रेस की छवि पर किसी ने भौंहें नहीं चढ़ायी थीं? उस समय तो इसे 'संजय माफिया' कहा जाता था। यह संगठन अपने 'नसबंदी अभियान' के लिए काफी बदनाम हुआ था। इसके बाद जनता पार्टी के कार्यकाल में (१९७७-७९) गांधी परिवार के समर्थन में सड़कों पर हिंसा फैलाने पर भी इसने काफी बदनामी हासिल की थी। लेकिन राजीव के आने के बाद और खास तौर पर बंगलौर में युवा कांग्रेस के सम्मेलन को सबोधित करने के बाद यह आशा की जा रही थी कि संगठन में 'शक्ति और उत्साह' का संचार होगा। लेकिन ५ वर्षों बाद परिणाम सिफर रहा।

उद्देश्य: पार्टी संविधान के अनुसार युवा कांग्रेस का उद्देश्य भारत के युवकों को संगठित करना, हर एक नागरिक को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना और उन्हें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश के निर्माण में सहयोग देने के लिए तैयार करना है। लेकिन इसके कितने सदस्य ऐसे हैं जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं? सत्ताधारी दल के एक सांसद और पूर्वमंत्री के अनुसार, "मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि एक प्रतिशत भी युवक कांग्रेस में ऐसे नहीं हैं जिन पर हम गर्व कर सकें।"

बहरहाल, राजीव गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद तीन लोग युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। वे हैं—तारिक अनवर, आनंद शर्मा और हाल में निर्वाचित गुरुदास कामथ। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने तारिक अनवर को कांग्रेस सेवादल का अध्यक्ष बना दिया (देखें बाक्स)। अनवर की जगह अप्रैल १९८५ में आनंद शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनमें आनंद शर्मा सबसे ज्यादा अवधि-दो साल आठ महीने तक-इस पद पर टिके।

आरोप: बहरहाल, युवा कांग्रेस की नयी समिति में आनंद शर्मा के आलोचकों की संख्या कम नहीं है। आलोचकों का आरोप है कि श्री शर्मा की रुचि सामाजिक कामों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रचार में थी। इस आरोप की पुष्टि के लिए वे 'गुट निरपेक्ष युवा सम्मेलन' (नयी दिल्ली, नवंबर १९८५), 'मास्कों युवा महोत्सव' तथा नवंबर '८७ में दिल्ली में हुई 'रंगभेद विरोधी सम्मेलन' में उनकी भूमिका का उदाहरण देते हैं।

लेकिन श्री शर्मा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देने के कारणों की चर्चा करते हुएं इन आरोपों का खंडन करते हैं। वह कहते हैं, " मैं जिस साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना (१९८५) वह अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष था। इसके अलावा क्या यह सत्य नहीं है कि आज के युवक कल के नेता होंगे और उन्हें विश्व के नेताओं और घटनाओं से रु-ब-रू होना चाहिए? आखिरकार भारत एक विश्व शक्ति है।"

बहरहाल, नये अध्यक्ष कामथ ने बेरोजगारी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है।

—प्रकाश नंदा

उमाशंकर दीक्षित

कांग्रेस कभी कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि इसने 'आंदोलन' की भूमिका निभायी है।

भूतपूर्व मंत्री व सांसद नवल किशोर शर्मा मानते हुए कहते हैं, "यह कथन सही है कि पार्टी के समर्थन आधार का क्षय हो रहा है, किंतु इसके इलाज का नुस्ख़ा घातक है।"

पिछले कुछ सालों में पार्टी के जन समर्थन में आयी कमी से स्पष्ट है। श्री गाडगिल कहते हैं "राजीवजी यदि कारगर कदम नही उठाते, तो पार्टी की विकट-विषम स्थिति बरकरार रहेगी" अल्पसंख्यक और हरिजन आदिवासी जो कि समाज के सबसे गरीब तबके हैं, कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक हैं। किंतु संपूर्ण भारत आधुनिकता की जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है, उससे अब यह आशंका व्यक्त की जाती है कि मात्र ये ही वर्ग पार्टी की विजय को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इस संबंध में किसानों व औद्योगिक श्रमिकों की बढ़ती ताकत एक अहम भूमिका निभायेगी।

यह जानना रोचक होगा कि छठी लोकसभा में ३६ प्रतिशत सांसद कृषिकर्मी थे। सातवीं लोकसभा में यह प्रतिशत बढ़कर ३८.७ प्रतिशत हो गया और मौजूदा लोकसभा में ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे सिद्ध होता है कि किसान अधिक सजग और संगठित हो गये हैं। यह उ०प्र० में महेन्द्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र में शरद जोशी, कर्नाटक में स्वामी के नेतृत्व में उभरते जबर्दस्त किसान आंदोलनों से उजागर है। यह सच है कि कांग्रेस पार्टी का अपना किसान प्रकोष्ठ है। मजेदार बात है कि गत दिसंबर में महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटील ने किसानों की मांग बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय शेतकारी संगठन की स्थापना की, किंतु कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक इसे पार्टी का मंच बनाने से इनकार किया है।

इसी तरह औद्योगिक श्रमिक तुलनात्मक रूप से अपनी सीमित संख्या के बावजूद अपनी एकजुटता और सजगता के कारण भारतीय मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह भी सच है कि देश की सर्वाधिक सदस्यता वाला (४३ लाख से अधिक) श्रमिक संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) से इसके सदस्य आश्चर्यजनक रूप से संगठन छोड़ते जा रहे हैं। इंटक के एक सचिव व बिहार के कांग्रेसी सांसद गोपेश्वर का कहना है कि संगठन अपने १० से १२ लाख सदस्यों को खो चुका है। "यह श्री गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाला संस्थान है, को समय-समय पर दी जाने वाली डांट-फटकार का एक नतीजा हो सकता है।" वह कहते हैं, "जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो प्रधानमंत्री तो हमारी बात सुनते हैं, पर उनके मंत्रीगण नहीं, जो बेकार हुई मशीनों जैसे हैं।"

उल्लेखनीय है कि भारतीय युवा दिल्ली में किसी पार्टी को सत्तारूढ़ या सत्ताविहीन करने में अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं। २१ से ४० की आयु समूह वालों की संख्या २१ करोड़ ६० लाख के लगभग है जो भारत की कुल आबादी का ५४ प्रतिशत है। ऐसे बृहद-विशाल मतदाताओं की माकूल देखरेख व पोषण आसान काम नहीं। खासकर तब जब बेरोजगारी की समस्या दिनोदिन

कांग्रेस सेवा दल

तारिक अनवर

कांग्रेस सेवा दल के उद्देश्यों और उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मौजूदा अध्यक्ष और सांसद तारिक अनवर का कहना है, "यदि युवा कांग्रेस को सक्रिय बनाने का श्रेय संजय गांधी को जाता है, तो कांग्रेस सेवादल को पुनर्जीवन देने का श्रेय राजीव गांधी को है।" वास्तव में, १९२३ में बने और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले इस संगठन की ओर राजीव गांधी ने ही ध्यान देना शुरू किया था। कांग्रेस सेवा दल के गठन के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य था कि इसके मार्फत कांग्रेसियों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाये। खास तौर पर दलितों की सेवा इसका उद्देश्य था।

सेवादल ने संस्थापकों की उक्त इच्छा को काफी हद तक पूरा किया और इसी वजह से १९३७ में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। १९३७ में कांग्रेस के कई राज्यों में सत्ता संभालने के बाद सेवादल ने फिर से काम शुरू किया। भारत ऐक्ट-१९५५ के कानून के तहत, जिसमें भारतीयों को सत्ता में भागेदारी के कुछ अधिकार दिये गये थे, उसी के चलते कांग्रेस सत्ता में आयी थी। लेकिन विभिन्न राज्यों की इकाइयों में सही तालमेल न होने के कारण सेवादल अपनी १९३२ के पहले वाली भूमिका नहीं निभा सका।

१९४७ में देश आजाद होने के बाद सेवादल आज वाली रूप रेखा ग्रहण कर सका। लेकिन बाद में कई मौकों पर यह साबित हो चुका है कि यह दल केवल कागजों पर ही चल रहा है। अनवर का कहना है, "मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में मैं इससे जुड़कर गर्व का अनुभव करता हूं।" अनवर के अनुसार उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ४० वर्ष से कम उम्र के सांसदों और विधायकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के बारे में राजनीतिक और आर्थिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से प्रशिक्षित करना रहा है। इस तरह का पहला प्रशिक्षण शिविर १९८६ में नैनीताल में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि यह प्रशिक्षण नियमित रूप से देने का विचार था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनवर के अनुसार केवल राज्य स्तर पर- राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों को बाद में भी प्रशिक्षित किया गया।

आपसी लड़ाई : अनवर इस का जवाब देने से कतराते हैं कि यह योजना सराहे जाने के बावजूद समुचित ढंग से क्यों नहीं चल पायी, लेकिन कारण समझना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि अनवर और आनंद शर्मा में ठनी हुई है।

सेवादल के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि संगठन की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। लेकिन वह यह भी कहते हैं, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मैं इससे बहुत ज्यादा काम करना चाहता था। जब मैंने यह पद संभाला था, तो मेरी इच्छा थी कि मतदान केंद्रों के स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं कर सका। वह इसका कारण साथियों का पूर्ण सहयोग न देने को मानते हैं।

पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने युवा कांग्रेस और सेवादल के बीच की इस स्थिति को टालने की काफी कोशिश की, खास तौर पर जब शर्मा और अनवर उनके विश्वसनीय सिपहसालार थे लेकिन इन दोनों के आपसी झगड़ों में वह चुप ही रहे।

—प्रकाश नंदा

भयावह रूप धारण करती जा रही होऔर सत्तासीन पार्टी कांग्रेस उसका सामना करने की स्थिति में कतई न हो।

पार्टी का युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस अपनी दयनीय स्थिति में लोगों को आकृष्ट करने (देखें बाक्स) और उन्हें कांग्रेस समर्थक बनाने में असमर्थ है। वैसे भी भारतीय राजनीतिक दलों के युवा संगठन शहरों तक ही सीमित हैं। चूंकि शहरी युवाओं की कुल संख्या डेढ़ करोड़ है और वे प्रायः सत्तारूढ़ पार्टी के विरोधी होते हैं, इसलिए कांग्रेस को १९८९ में मतदान के समय जाते हुए इस संकट का सामना करना पड़ेगा।

इस समूची पृष्ठभूमि में पार्टी के क्षेत्रीय आधार में एक महत्वपूर्ण बदलाव पिछले पांच वर्षों में आया है। सभी चार दक्षिणी राज्यों-आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल के कांग्रेस के मजबूत गढ़ ढह गये हैं। पश्चिमी क्षेत्र-महाराष्ट्र व गुजरात में भी पार्टी की स्थिति डांवाडोल है। पूरब में केवल एक महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा में कांग्रेस सत्ता में तो जरूर है, किंतु गत तीन वर्षों में विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों में वह सभी सात सीटों पर पराजित हुई है।

शेष बचे हिंदी भाषी क्षेत्रो में सात राज्य और संसदीय सीटों का ४२ प्रतिशत भाग आता है। कांग्रेस को १९८४ के चुनावों में असाधारण सफलता प्राप्त हुई जबकि उसने इतिहास में पहली बार सभी प्रमुख राज्यों उ०प्र०, बिहार, म०प्र० व राजस्थान में ५० प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये। किंतु यह राजनीतिक रूप से अत्यधिक गतिशील क्षेत्र है जिसने अतीत में कांग्रेस को जबर्दस्त आघात भी पहुंचाया था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस क्षेत्र में आंधी चलने के बाद कांग्रेस को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, विशेषकर हरियाणा चुनावों में इसकी अभूतपूर्व पराजय को देखते हुए।

वी०एन० गाडगील

पहले कांग्रेस में वर्षों सक्रिय कार्यकर्ता होने वाले को ही संसद या विधानसभा का टिकट मिलता था। किंतु गत कुछ वर्षों से यह परंपरा ताक पर रख दी गयी।

बहरहाल, "अभी भी हमने कुछ नहीं खोया। हम हर दस वर्ष बाद पार्टी में एक जबर्दस्त उथलपुथल के साक्षी रहे हैं। १९६७ में **पार्टी** विभाजन के बाद तमाम दिग्गज नेता हमें छोड़कर चले गये थे। १९७७ में हमारी गद्दी छिन गयी थी। १९८७ में भी वही हुआ और पार्टी संकटों से गुजरी। अब वह काल बीत गया है," आशावादी कांग्रेस महासचिव के०एन० सिंह कहते हैं।

भारत का विभाजित विपक्ष कभी भी दो पार्टी प्रणाली के हित में नहीं रहा है जैसा कि पश्चिमी देशों के लोकतंत्र में है। इसीलिए शासक पार्टी की तमाम खामियों के बावजूद कांग्रेस के कट्टर विरोधी आर०एस०एस० के सरसंघचालक बालासाहब देवरस तक कहते हैं, "वर्तमान समय में कांग्रेस नेतृत्व का देश में कोई विकल्प मुझे नहीं दिखायी देता।" इस विचार से अधिसंख्य लोग सहमत हैं।

इंदिरा गांधी 'प्रतिभाशाली' नेता थीं। किंतु उनके बेटे ने अभी तक ऐसा कोई चिह्न नहीं दिखाया। वह भविष्य से इतने अभिभूत हैं कि अतीत को अनदेखा कर उससे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। प० बंगाल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री ज्योति बसु जैसे कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तक की टिप्पणी है, "मुझे भय है कि यदि इंदिरा गांधी आज जिंदा होतीं, तो आज के कांग्रेसी उन्हें भी खारिज कर देते। आज कांग्रेस पार्टी के नौजवानों की निगाह में शायद वह बहुत बूढ़ी सिद्ध होतीं।" और शायद यही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा और अहम संकट है।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव, सुनील सक्सेना

—प्रकाश नंदा

कार्य कुशल

रीटा

सिलाई मशीन

अनेक घरेलू एवं औद्योगिक मॉडल्स में उपलब्ध

IS:1610

ISI

Rita

जीवन पर्यन्त सेवा के लिए निर्मित

adEnvoys

चुनाव क्यों टाले गये ?

जिस दिन चुनाव आयोग को इलाहाबाद, पाली, गोधरा, सिरसा, फरीदाबाद, ऊधमपुर, कालीकट लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनावों और दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करनी थी, उस दिन उसने इन चुनावों और उपचुनावों को फिलहाल मुल्तवी करने की घोषणा कर दी और कारण बताया गया शांति और व्यवस्था के बिगड़े हालात को। लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि शांति-व्यवस्था का तो बहाना बनाया गया है—असली वजह है, कांग्रेस-इ की पराजय का भय, लेकिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि जनता का कांग्रेस-इ पर अटूट विश्वास कायम है और उनके कार्यकाल में हुए १९ संसदीय उपचुनावों में कांग्रेस-इ ने १३ उपचुनावों में विजय प्राप्त की है। फिर इन चुनावों को स्थगित करने के पीछे असली कारण कौन से हैं? क्या एकजुट होने की कोशिश में लगे विपक्ष की शक्ति को बिखेर देने के लिए यह मध्यावधि चुनावों का पूर्व संकेत है? जिस चुनाव-आयोग पर चुनाव कराने का दायित्व है, वह चुनाव मुल्तवी करने का कार्य क्यों कर रहा है? चुनाव टाले जाने से क्या कांग्रेस-इ की स्थिति मजबूत होगी या काले धन और दलाली प्रकरणों से बदनाम हो रही कांग्रेस-इ की छवि पर और भी गहरी कालिख पुत जायेगी? :

चुनाव आयोग ने सूखे की विभीषिका और कानून-व्यवस्था की बिगड़ी हालत के कारण आठ संसदीय उपचुनावों, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली महानगर परिषद के चुनावों को स्थगित कर दिया है। लेकिन उक्त दोनों ही कारण किसी के गले नहीं उतर रहे। सूखे का संकट है, तो फिर स्वयं प्रधानमंत्री सरिस्का बैठक और लक्षद्वीप की यात्रा जैसे अनावश्यक खर्चीले आयोजन क्यों कर रहे हैं और सूखे से प्रभावित देश की सर्वाधिक आबादीवाले प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने

राजनीतिक कुश्ती के लिए आतुर:
मदनलाल खुराना

विधानसभा की स्वर्ण जयंती सादगी से न मनाकर, इस पर करोड़ों रुपए क्यों फूंक दिये? यदि कानून-व्यवस्था की बिगड़ी हालत निष्पक्ष चुनावों के लिए बाधक है, तो त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव कराने की घोषणा क्यों की गयी, जबकि वहां आतंकवादी हत्याएं जारी हैं।

हार का भय: वस्तुत: राजनीति के पंडित जानते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संकेत व निर्देश से ये चुनाव टाले गये हैं। कालेधन और दलाली प्रकरण से बदनाम होती कांग्रेस की छवि; बिगड़ती आर्थिक स्थिति, विधान सभा चुनावों में एक के बाद एक प्रांतों का कांग्रेस-इ के हाथों से निकलना, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बढ़ती खाई, आदि ऐसे स्पष्ट कारण हैं, जो इन चुनावों में कांग्रेस-इ की आसन्न पराजय का संकेत दे रहे थे। हाल ही महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के दो संसदीय उपचुनावों में कांग्रेस-इ की पराजय भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक सीधा आघात थी। उल्लेखनीय है कि जिन सीटों के चुनाव स्थगित किये गये हैं, प्राय: उन सभी स्थानों पर कांग्रेस-इ को अपनी पराजय के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में उसकी हवा बिगड़ी हुई है (देखिए बाक्स)। बताया जाता है कि आई०बी० (गुप्तचर विभाग) ने दिल्ली चुनाव संबंधी रिपोर्ट में कांग्रेस को केवल दस सीटें ही मिलने का संकेत दिया था। प्रतिष्ठा की सीट इलाहाबाद में प्रधानमंत्री के अंतरंग बालसखा सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की विवादग्रस्त छवि ने उपचुनाव में कांग्रेस-इ की विजय को संदिग्ध बना दिया है। दूसरी ओर, छह मास पूर्व राजीव गांधी ने कांग्रेस-इ के चार लाख कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की जो महायोजना तैयार की थी, वह भी असफल हो गयी है। कहा जाता है कि हार का मुंह देखने की अपेक्षा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसी में खैरियत समझी कि भले ही कुछ समय के लिए ही सही, ये चुनाव स्थगित करा दिये जायें।

अरुण नेहरू

कांग्रेसी नेतृत्व की गति सांप-छछूंदर जैसी हो गयी है। यदि शीघ्र चुनाव कराते हैं, तो हार की संभावना के अतिरिक्त पार्टी खेमे में उथल-पुथल और पाला बदल का सामना करना पड़ेगा। यदि टालते हैं, तो विपक्ष को अधिक संगठित, एकजुट और जनता के मध्य अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा मौका प्रदान करते हैं। साथ ही अपने दल में फैलते असंतोष के परिणामस्वरूप बिखराव-विघटन को दावत देते हैं।

बहरहाल, कांग्रेसी खेमा 'हार के भय' को चुनाव-स्थगन का कारण मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वयुवा कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद आनंद शर्मा ने इसे मिथ्या करार देते हुए दावा किया, "चुनाव स्थगन की आलोचना अवांछित और अन्यायपूर्ण है। ऐसे आलोचक सुविधावश यह भूल जाते हैं कि पिछले दिनों ही हमने नागालैंड में चुनाव कराये थे और विजयश्री प्राप्त की थी। यही नहीं, अगले महीने त्रिपुरा और मेघालय में भी विधिवत चुनाव कराये जा रहे हैं। कांग्रेस मतदाताओं से मुंह कतई नहीं छिपा रही है। किंतु क्या इसके चलते हम देशव्यापी सूखे की भयावह समस्या से आंखें फेर लें? विपक्ष समस्या का राजनीतिक लाभ उठाने की जगह कोई ठोस और रचनात्मक कार्य क्यों नहीं करता?"

कांग्रेसी ही नाराज: बहरहाल, यह वास्तविकता है कि चुनाव-स्थगन से सर्वाधिक बेचैनी और आक्रोश कांग्रेसी खेमे में ही व्याप्त है। इसके दो प्रमुख कारण बताये जा रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने यह निर्णायक कदम पार्टी जनों से किसी भी स्तर पर सलाह-मशविरे के बिना महज कंप्यूटर की सलाह पर उठाया, वह भी बिना किसी स्पष्ट रणनीति के तहत। दूसरे, पार्टी के प्रबुद्ध, विवेकशील और जनता की नब्ज पहचाननेवाले वर्ग का मानना है कि यह फैसला सरासर गलत है। फौरी लाभ को देखते हुए पार्टी के दूरगामी हितों को बलि पर चढ़ाया गया है।

इस फैसले से आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल क्षीण हुआ है, इसमें संदेह नहीं। यही उनके बीच फैलते संशय और आतंक का मूल कारण भी है। जनता से जो आज उन्हें आंख चुरानी पड़ रही है, उसकी भारी कीमत उन्हें आगामी काल में चुकानी पड़ेगी, यह बात वह भलीभांति जानते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के अनुसार, "स्थिति नाजुक और गंभीर है। इस बात की सूचना और पार्टीजनों की मनोभावना से प्रधानमंत्री को भी अवगत करा दिया गया है।"

दिल्ली के सत्ता गलियारों में यह समाचार जोर पकड़ रहा है कि १४० इंका सांसदों के बीच हुई बातचीत में सर्वसम्मत से यही निष्कर्ष निकाला गया है कि चुपचाप बैठ कर तमाशा देखने का समय निकल चुका है। यदि पार्टी को वर्तमान संकट और भावी पराजय से बचाना है, तो प्रधानमंत्री को अपनी कार्यशैली में मूलगामी परिवर्तन करने होंगे। सर्वप्रथम, उन्हें अपने अराजनीतिक सलाहकारों से छुटकारा पाना होगा। अकेले निर्णय लेने की अपेक्षा वरिष्ठ, अनुभवी नेताओं से मंत्रणा करते रहना ही बेहतर होगा। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भावी

साक्षात्कार/श्यामलाल शकधर

पूर्व चुनाव आयुक्त

हार के डर से चुनाव टाले गये

वह पर्वतीय क्षेत्र के वासी ही नहीं, पर्वतीय लोगों जैसे सहज-सुदृढ़ भी हैं। अडिग निष्ठा और समर्पण भाव से गुरु-गंभीर उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक वहन करनेवाले सत्तर वर्षीय श्यामलाल शकधर का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निष्पक्ष, विवेकपूर्ण, जांचपरख और बेलाग फैसलों के यादगार कारनामों से परिपूर्ण था। चुनाव मामलों में उजागर मौजूदा अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैये से पीड़ित-व्यथित श्री शकधर ने स्वयं तीन सरकारों (इंदिरा गांधी, चरण सिंह व मोरारजी देसाई) को सफलतापूर्वक झेला भी है। प्रस्तुत हैं, 'माया' से उनकी बातचीत के अंश:—

माया: दिल्ली के स्थानीय चुनावों और इलाहाबाद के संसदीय उपचुनाव को टालने के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

शकधर: यह एक गलत कदम है। इसका संविधान की विश्वसनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र की असली कसौटी चुनाव ही है। उसको हर हालत में संपन्न करना लाजिमी है।

माया: क्या ऐसा हार के डर से किया गया है?

शकधर: निश्चय ही। इसके अतिक्ति कोई अन्य कारण नजर नहीं आता।

माया: दिल्ली चुनावों को टाले जाने का मुख्य कारण उसे राज्य का दर्जा देना बताया जा रहा है। क्या यह कारण चुनाव टालने के लिए माकूल है?

शकधर: दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात १५ वर्षों पुरानी है, जिसे अकसर जांचा-परखा गया है। मेरी समझ में यह मुद्दा चुनाव टालने का कोई वजनदार कारण नहीं है। चुनाव आयोग का मुख्य काम चुनाव पूरा कराना है, मुल्तवी कराना नहीं। असाधारण स्थितियों मसलन, विदेशी आक्रमण, गृहयुद्ध और आंतरिक कानून-व्यवस्था के पूर्णतया विफल हो जाने पर ही चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण आज दरपेश नहीं है।

माया: क्या यह भविष्य में भी चुनावों को टाले जाने का एक संकेत है?

शकधर: संभव है। श्रीमती गांधी यही कदम उठाकर खमियाजा भुगत चुकी थीं। राजीव गांधी का भी यही हश्र हो सकता है। आग में जो हाथ डालेगा उसकी उंगलियां निश्चय ही जलेंगी।

माया : चुनाव आयोग पर मुख्य आरोप है कि वह अनियमित तरीके से सरकार का पक्षधर बना है। क्या आप इससे सहमत हैं?

शकधर : यह कहना मुश्किल है। किंतु मैं एक अखबार में छपी इस खबर से अत्यधिक चिंतित हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री पेरी शास्त्री ने सरकार से चुनाव कानून में संशोधन द्वारा निश्चित दिशा निर्देश देने की मांग की है। ऐसा लगता है कि अपनी अक्षमता छिपाने के लिए वह इसकी छतरी के नीचे छिपना चाहते हैं।

माया : क्या आपको लगता है कि दिशानिर्देश मांग कर वह अपने अधिकारों का समर्पण कर रहे हैं?

शकधर : संविधान द्वारा चुनाव आयोग को संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारों का महत्व इसी से है कि मात्र भारतीय संविधान में इसके अधिकारों का विवरण उल्लिखित है।

माया : चुनाव आयोग के अधिकार क्या प्रधानमंत्री के अधिकारों से ऊपर हैं?

शकधर : प्रधानमंत्री ही नहीं, चुनाव आयोग तो संसद द्वारा पारित कानून से भी ऊपर है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बहुत कुछ करने का अधिकार रखता है। यहां तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून भी बदल सकता है। समझ में नहीं आता कि वह अपने इन व्यापक अधिकारों को किसी को छीनने का मौका क्यों देना चाहता है? यह किसी सरकारी दबाव के चलते किया गया लगता है।

माया : मुख्य चुनाव आयुक्त पर किस प्रकार दबाव डाले जा सकते हैं?

शकधर : यह सीधे या प्रधानमंत्री के दूतों द्वारा किया जा सकता है। श्रीमती गांधी सीधे बात नहीं करती थीं। प्रभाव डालने का प्रयास भी संवैधानिक तरीकों से किया जाता है। कांग्रेस सूत्रों ने प०बंगाल के चुनाव के दौरान मुझसे कहा कि मतदाता सूची अधूरी और गलत है। जांच करने पर मुझे इस आरोप में अतिशयोक्ति नजर आयी। कोई भी मतदाता सूची शतप्रतिशत सही नहीं होती। उन दिनों अजित पांजा प०बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वह पुनः मेरे पास मतदाता सूचियों की गलतियों की शिकायत लेकर आये। उनका दावा है कि मतदाता सूची में या तो लोगों के नाम ही नहीं थे या मरे हुए लोगों के नाम थे। मैंने जांच के लिए टीम भेजी, तो पता चला कि जिसको उन्होंने मृत बताया था, दरवाजा उसी ने खोला। अतः मैंने कांग्रेसी इच्छा के विरुद्ध चुनाव संपन्न कराने का दृढ़ निर्णय ले लिया। सिद्धार्थशंकर राय, अजित पांजा और ए०के०सेन ने तब मेरे इस निर्णय के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। कलकत्ता उच्चन्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। उन्होंने ऐसे कानूनी निर्देश दिये जिनसे एक वर्ष के लिए चुनाव टल गया। हमने इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती के सम्मुख पेश हुई। आमतौर से चुनाव आयोग के मुकदमे महाधिवक्ता द्वारा लड़े जाते हैं। किंतु पहली बार मैंने इसके विरुद्ध एफ० नारीमन को आयोग का वकील नियुक्त किया। अंततः जीत हमारी हुई और चुनाव विधिवत संपन्न हुए।

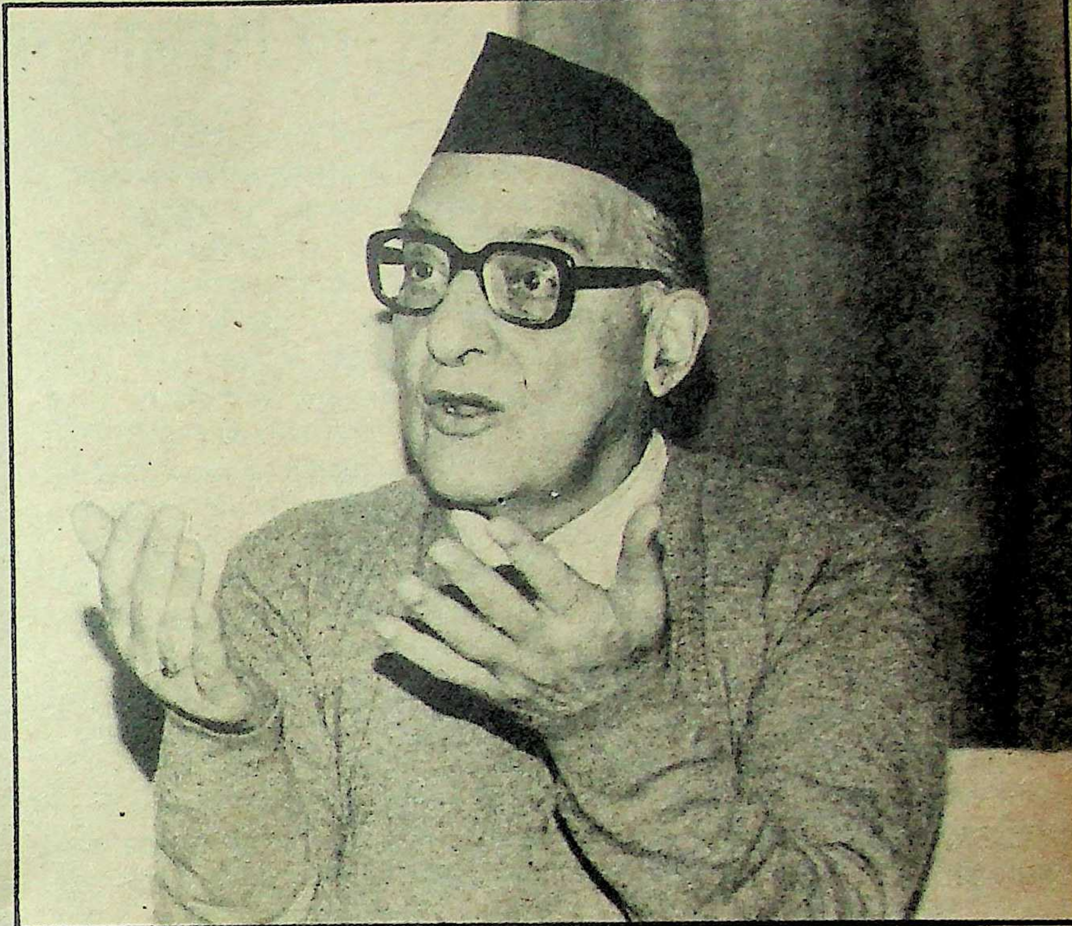

माया : यदि आप मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त होते, तो क्या चुनाव मुल्तवी कराने के लिए राजी होते?

शकधर : कदापि नहीं। जैसा कि मैंने प०बंगाल के चुनावों के मामले में कदम उठाया था, जबकि मुझे पता था कि श्रीमती गांधी स्वयं उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के पक्ष में कतई नहीं थीं।

माया : क्या आपके इस फैसले से श्रीमती गांधी क्रुद्ध नहीं हुई थीं?

शकधर : पता नहीं। इस बारे में उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। वह शांत प्रकृति की महिला थीं। मैंने कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न ही नहीं कराये, बल्कि श्री बहुगुणा ने जब कांग्रेस की बोगस मतदान कराने की शिकायत की, तो चुनाव को रद्द भी कराया। उस समय भी श्रीमती गांधी सत्ता में थीं और मेरा यह निर्णय सीधे उनके खिलाफ जाता था।

माया : क्या श्रीमती गांधी ने कभी इसका बदला लेने का प्रयास किया?

शकधर : नहीं। उनका लोकतंत्र में विश्वास था। व्यक्तिगत तौर पर वह बहुत ईमानदार थीं। वस्तुतः उन्होंने इस मामले में संसद में मेरा पक्ष लेकर बचाव भी किया था।

माया : क्या संवैधानिक तरीकों के अलावा भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा सकता है?

शकधर : अवश्य। प्रलोभन और तरक्की का आश्वासन देकर भी मनचाहा दबाव डाला जा सकता है। वैसे इस संबंध में मेरा कोई निजी अनुभव नहीं है।

माया : मुख्य चुनाव आयुक्त की भावी महत्ता को देखते हुए कैसे व्यक्ति की नियुक्ति इस पद पर की जानी चाहिए?

शकधर : यह कहना कठिन है। प्रधानमंत्री और मंत्री बनने का भी तो कोई मापदंड नहीं है। किंतु ऐसे पदों पर ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति का होना आवश्यक है।

माया : यदि चुनाव आयुक्त पर ऐसे दबाव बढ़ते गये, तो इसका नतीजा क्या होगा?

शकधर : बहुत बुरा। संविधान की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जायेगी।

माया : पाकिस्तान और बांगलादेश में चुनाव निरंतर टाले जाते रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसा संभव है?

शकधर : मैं नहीं समझता कि भारत में ऐसी कोई तरकीब सफल हो सकती है।

—रंजना कक्कड़

क्यों टाले गये दिल्ली-चुनाव ?

बात कोई पुरानी नहीं। ४-५ सप्ताह पूर्व ही 'माया' की कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस से लम्बी बातचीत हुई थी। चूंकि दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद चुनाव सिर पर थे और श्री फर्नांडीस पर ही पार्टी की दिल्ली इकाई के मामलों की देखरेख का भार है, इसलिए बात भावी चुनावों और उसके परिणामों पर आ टिकी। फर्नांडीस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, "कांग्रेस की विजय निश्चित है। पिछले वर्षों हमने दिल्ली की इतनी अधिक सेवा की है कि किसी अन्य नतीजे की गुंजाइश ही नहीं। आप किसी भी झुग्गी-झोंपड़ इलाके में जाकर खुद देख लें। झंडे कांग्रेस के ही लहराते मिलेंगे।"

भाजपा की संभावित चुनौती की चर्चा चली, तो दोटूक उत्तर मिला, "जब सत्ता में रहते उन्होंने दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? वैसे भी जो शरणार्थी उनके पारंपरिक मतदाता थे, वे अब शरणार्थी नहीं, पूरे दिल्लीवासी बन गये हैं और अच्छी तरह जानते-समझते हैं कि उनके हितों की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है।"

बात आयी-गयी हो गयी। यद्यपि भाजपा भी अपनी संभावित सफलता का राग अलापने का मौका नही गंवा रही थी। दोनों ही खेमों में तैयारी पूरे जोश-खरोश से जारी रही।

यकायक १६ दिसम्बर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने प्रेस कांफ्रेंस बुला कर आरोप लगाया कि इंका सरकार दिल्ली में गोवा के तर्ज पर तीसरे दर्जे की विधानसभा का झांसा देकर महानगर और दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालने का षड्यंत्र रच रही है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि भाजपा को सरकार द्वारा मंगवायी ऐसी रिपोर्ट की पूर्वसूचना मिल गयी थी। जवाब में प्रदेश इंका अध्यक्ष ताजदार बाबर ने कहा, "पता नहीं श्री खुराना को कहां से तार मिला है कि चुनाव टाले जा रहे हैं।" उपाध्यक्ष रामलाल ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, "भाजपा दिल्ली में गोयबल्स की तरह बार-बार झूठ बोलकर यह जताना चाहती है कि दिल्ली में इंका की हालत पतली है और हार से बचने के लिए वह चुनाव टालना चाहती है।"

अध्यादेश: अन्ततः हुआ भी यही। २४ दिसम्बर रात दस बजे पी०टी०आई० को चुनाव मुल्तवी करनेवाले अध्यादेश की सूचना दे दी गयी। उल्लेखनीय है कि परिषद का कार्यकाल एक दिन पूर्व ही समाप्त हुआ था और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को भी इसका ज्ञान नहीं था। उस दिन भी सदन में यथासमय चुनाव कराने की घोषणा की गयी थी। श्री खुराना के अनुसार विजय कुमार मल्होत्रा के साथ २१ दिसम्बर को ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से भेंटकर चुनाव संबंधी पूछतांछ की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आयोग दो राज्यों—त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ दिल्ली चुनावों के लिए तैयार है। अतः यकायक ऐसा क्या संकट आ गया कि अध्यादेश जारी कर, वह भी संसद सत्र की समाप्ति के फौरन बाद ही, दिल्ली चुनाव स्थगित करा दिये गये?

औपचारिक रूप से फैसले को गैरराजनीतिक दिखने से बचाने के लिए न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर उसे दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के अध्ययन का कार्यभार सौंपा गया है। भारत सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली में कई प्रमुख संस्थाएं होने से अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। यह सवाल संसद सहित अन्य मंचों से भी निरन्तर उठाया जाता रहा है। अतः इस पर विचार और नया कदम उठाना जरूरी माना गया। लेकिन यह दलील किसी भी विपक्षी दल के गले से नीचे नहीं उतरती। सभी समिति को हार से बचने का बहाना मात्र मानते हैं। विपक्षी खेमे में रोष स्वाभाविक है। उनका कहना है कि यदि समिति ही बनानी थी, तो ऐन चुनाव के समय ही क्यों? आगे या पीछे क्यों नहीं? चुनाव अधिसूचना जारी करने में केवल तीन ही दिन बाकी रहने पर अध्यादेश जारी करना दिल्ली के मतदाताओं के साथ धोखा और अन्याय नहीं, तो और क्या है?

भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी तो अध्यादेश को ही सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करार देते हैं। उनका कहना है, "यह अधिकार सरकार को असाधारण अवस्था में जारी करने के लिए दिये गये हैं। संसद सत्र की समाप्ति के एक सप्ताह बाद ही अध्यादेश जारी करना किसी तरह उचित नहीं।"

श्री आडवाणी के अनुसार चुनाव मुल्तवी होने की बयार पिछले तीन महीनों से चल रही थी। इसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस इस समय मतदाताओं के सम्मुख जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे मालूम है कि सरकार और व्यवस्था विरोधी माहौल राष्ट्रव्यापी है।

खुफिया रिपोर्टें: चुनाव टलवाने में खुफिया रिपोर्टों ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। करारी हार के संकेतों के अतिरिक्त इनमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ की जबरदस्त गुटबाजी का भी पूर्ण ब्यौरा है। इसकी जांच के लिए आस्कर फर्नांडीस ने ४० ब्लाकों में बैठकें आयोजित कीं। आपसी फूट और आन्तरिक कलह का अन्दाज उन्हें इसी बात से हो गया कि प्रत्येक सभा में विभिन्न नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर गाली-गलौज से लेकर चाकूबाजी तक की वारदातें हुईं। श्री फर्नांडीस के लिए इन विवादों को निपटाना और कठिन था, क्योंकि केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री हरकिशन लाल भगत और केन्द्रीय नगर विमानन और पर्यटनमंत्री जगदीश टाइटलर जैसे दिग्गज नेता इनमें उलझे थे। वैसे भी हार के डर से दोनों ही चुनाव संबंधी जिम्मेदारी लेने में आनाकानी कर रहे थे। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जगदीश टाइटलर ने पहले ही यह जिम्मेदारी श्री भगत पर थोपनी चाही थी, किंतु राजनीति के पुराने खिलाड़ी हरकिशन लाल भगत भी साफ दामन बचा गये। केन्द्रीय संचारमंत्री अर्जुन सिंह से ही चुनाव स्थगन की मांग कर रहे थे। अतः सरकार और इंका ने इसी में खैरियत समझ चुनाव स्थगन के निर्णय को खैरख्वाही का जामा पहनाने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि जिस गुटबाजी के डर से चुनाव टाले गये, उनमें अब और तेजी आ गयी है।

चुनाव स्थगन के पीछे एक अम्य कारण यह भी माना जा रहा है कि टिकट काफी नये लोगों को दिये जाते। वैसे भी उम्मीदवारों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। अतः इस बात का पूर्ण अन्देशा था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, वही ज़ड़ खोदने में जुट जायेंगे या इंका से पलायन करेंगे। यह पार्टी की गिरती साख को मिट्टी में मिलाने के लिए पर्याप्त होता। इंका के पास चुनाव रोकने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं था।

लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने में प्रधानमंत्री ने न कभी देर की, न संकोच। न ही कभी आलोचना पर ध्यान दिया। अतः चुनाव मुल्तवी करने का निर्णय लेना उनके लिए कठिन न था। दिल्ली की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का उन्हें क्या सजा देगी, यह तो समय ही बतायेगा, किंतु विपक्ष आश्वस्त है कि उन्हें अपने किये की सजा आज नहीं, तो कल भुगतनी ही पड़ेगी।

—रंजना कक्कड़

सलाहकारों में वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी और मानव संसाधन मंत्री पी०वी० नरसिम्हाराव के नाम सर्वोपरि हैं।

पार्टीजनों का यह खुला आक्रोश और चुनौतीपूर्ण रवैया तीन वर्ष के राजीव शासनकाल में शायद प्रथम बार उभरकर आया है। परिणामतः विपक्ष को एक नयी आशा ने प्रोत्साहित कर दिया है। अनेक विपक्षी नेताओं के अनुसार कांग्रेस के जिस अपेक्षित विभाजन को विश्वनाथ प्रताप सिंह हासिल करने में अब तक असमर्थ रहे थे, वह राजीव गांधी के 'प्रयासों' द्वारा पूर्ण हो जायेगा। इसी कारण आगामी बजट सत्र और केंद्रीय मंत्रिमंडल में निकट भविष्य में संभावित फेरबदल के उपरांत वह कांग्रेसी खेमे से भगदड़ की शुरुआत की आशा लगाये बैठे हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल विपक्षियों की मनोकामना मात्र ही रह जायेगी?

भगदड़ की चर्चा जब एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से चली, तो वह हंसकर बोले, "लगता है कि ऐसा दिवास्वप्न विपक्ष मूल कांग्रेसी चरित्र को भूलकर देख रहा है। कांग्रेसियों का एक प्रमुख गुण है, सत्ता से अटूट, अभिन्न लगाव। 'जब तक सांस, तब तक आस' उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। इस समय एक तो दल-बदल विरोधी कानून उनके पैरों में बेड़ियां डाले हुए है। दूसरे कुरसी प्रेम और अन्य प्रलोभन उनको बांधे रखेगा।"

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कांग्रेसी चरित्र की इस कमजोरी का प्रधानमंत्री और उनकी अंतरंग टोली पूरा लाभ उठा रही है। प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने कुछ समय पूर्व यह उद्घाटित कर सबको चौंका दिया था कि १५० से अधिक कांग्रेसी सांसदों को मंत्री-पद का वायदा किया गया है। लगभग ऐसी ही स्थिति विभिन्न राज्यों में भी है, जहां एक से अधिक लोग मुख्यमंत्री की कुरसी पर शोभित होने की आस लगाये बैठे हैं। समस्या तो तब विकट रूप धारण करेगी, जब अधिकांश नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर जायेगा। राजीव गांधी द्वारा वांछित और प्रत्याशित फेरबदल में हिचकिचाहट का यही मूल कारण माना जा रहा है।"

जाहिर है कि यह स्थिति बहुत दिनों तक चलनेवाली नहीं। कारण, अनेक विभाग और मंत्रालय सिरमौर रहित हैं अथवा प्रधानमंत्री सहित विभिन्न वरिष्ठ मंत्रियों के पास अनेक विभागों का कार्यभार है। इसे कुशलतापूर्वक ढो सकना किसी के लिए भी संभव नहीं। समस्या का शीघ्र समाधान ढूंढ़ना प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य है। यही नहीं, हाल में लगाये गये नये करों विशेषतया पेट्रोल की रेकार्ड मूल्य वृद्धि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की संभावित महंगाई के कारण, कांग्रेसी यह जान गया है कि जनता के व्यापक असंतोष, आक्रोश का सीधा निशाना चुनाव के दौरान उसे ही बनना पड़ेगा। आगामी बजट सत्र में गरमागरमी बढ़ने के आसार अभी से नजर आने लगे हैं। जैसा कि एक कांग्रेसी पदाधिकारी ने स्वीकारा, "भगदड़ न भी सही, तो भी भविष्य में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखना लोहे के चने चबाने जैसा होगा।"

कांग्रेस का कोई भी नेता यह खुलकर बताने की स्थिति में नहीं है कि यह चुनाव कब कराये जायेंगे? यह तो सभी मानते हैं कि बीच के समय को कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में लगायेगी, किंतु यदि निर्धारित समय में (जैसे दिल्ली चुनाव एक वर्ष के लिए पुनः टाले गये हैं) कांग्रेस अपने लक्ष्य में असफल होती है, तो उसका अगला कदम क्या होगा? चूंकि दिल्ली चुनाव संबंधी अध्यादेश में इस अवधि को एक-एक कर तीन साल तक बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए विपक्ष, विशेषकर दिल्ली चुनाव में मैदान फतह करने के दावेदार भाजपा का मानना है कि कांग्रेस अपनी तिकड़मबाजी से आगे भी चुनाव टालकर सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करेगी। किंतु लोकतांत्रिक प्रणाली में यह कब तक संभव है?

ऊह... आह... आउच को दूर भगाइए !

बदन दर्द और पीठ दर्द पर भी उसी तरह ध्यान देने की ज़रूरत है जैसे कि मोच, पेशियों में खिंचाव और जोड़ों की जकड़न पर.

इसलिए आयोडेक्स हमेशा अपने पास रखिए.

आयोडेक्स न सिर्फ़ दर्द से छुटकारा दिलाता है बल्कि चोट खायी कोशिकाओं को भी अच्छा करता है.

और आयोडेक्स दिन में दो बार मलें तो दुगुना फ़ायदा मिले.

इसलिए 'ऊह', 'आह' और 'आउच' को दूर भगाने के लिए आयोडेक्स लगाइए, और काम पर जाइए.

HTA 1711

आयोडेक्स®
मलिए,
क़ाम पर चलिए.

SKF— एस के एफ़ का उत्पादन.

आनंद शर्मा

> **इक्का-दुक्का को छोड़ अन्य लोगों के पार्टी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस से जो भी 'हीरो' बनकर गयी है, वह 'जीरो' बन, सिर झुका, घुटनों के बल वापस आया है। भगदड़ का शोर विपक्ष की कूटनीति का नमूना है। यह सत्य है कि १९८७ हमारे लिए कठिनाइयों से भरा था, किंतु हम उन पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हमारा आत्मविश्वास सुदृढ़ है। हमारे पास पर्याप्त शक्ति और साहस के अतिरिक्त सही नेतृत्व भी है।**

सांसद आनंद शर्मा भगदड़ की बात सुनते ही उत्तेजित स्वरों में कहते हैं, "इक्का-दुक्का को छोड़ अन्य लोगों के पार्टी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस से जो भी 'हीरो' बनकर गया है, वह 'जीरो' बन, सिर झुका, घुटनों के बल वापस आया है। भगदड़ का शोर विपक्ष की कूटनीति का नमूना है। यह सत्य है कि १९८७ हमारे लिए कठिनाइयों से भरा था, किंतु हम उन पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हमारा आत्मविश्वास सुदृढ़ है। हमारे पास पर्याप्त शक्ति और साहस के अतिरिक्त सही नेतृत्व भी है। पिछले वर्ष की क्षति की भरपाई हम शीघ्र ही कर लेंगे।"

लेकिन अरुण नेहरू के अनुसार, "कांग्रेसी नेतृत्व की गति सांप-छछूंदर जैसी हो गयी है। यदि शीघ्र चुनाव कराते हैं, तो हार की संभावना के अतिरिक्त पार्टी खेमे में उथल-पुथल और पाला बदल का सामना करना पड़ेगा। यदि टालते हैं, तो विपक्ष को अधिक संगठित, एकजुट और जनता के मध्य अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा मौका प्रदान करते हैं। साथ ही अपने दल में फैलते असंतोष के परिणामस्वरूप बिखराव-विघटन को दावत देते हैं।"

मध्यावधि चुनाव का अंदेशा: बहरहाल, राजनीति के ऐसे विशेषज्ञों की भी कमी नहीं है जो यह मानते हैं कि राजीव गांधी ने इन उपचुनावों सहित दिल्ली चुनाव स्थगित करने का फैसला दूरगामी रणनीति के तहत किया है। बताया जाता है कि उनके कंप्यूटरी आंकड़े और कुछ पत्रिकाओं के मत संग्रह आम चुनावों में कांग्रेस-इ की विजय के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। अत: इन उपचुनावों और दिल्ली चुनाव में हार की आशंका से बचने के लिए कुछ समय बाद यदि मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी जाये, तो एकजुट होने की कोशिश में लगी विपक्षी ताकतों में बिखराव आ जायेगा और राजीव गांधी को आगामी पांच वर्षों के लिए सत्ता में बने रहने का जनादेश मिल जायेगा।

दूसरी ओर सुब्रह्मण्यम स्वामी का कहना है कि आम चुनाव में कांग्रेस-इ विजय के कंप्यूटरी निष्कर्ष सही नहीं हैं, क्योंकि इसमें विपक्षी एकता की परिकल्पना शून्य मानकर निष्कर्ष निकाले गये हैं और यदि चार दलीय मोर्चे (लोकदल-अ, जनमोर्चा, जनता और कांग्रेस-स) को तेलुगु देशम और द्रमुक का सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो विपक्ष ३०४ सीटों का दावेदार हो जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि कंप्यूटरी मुगालते में कहीं राजीव गांधी ने मध्यावधि चुनाव करा दिये, तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। बहरहाल, भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नजर नहीं आती। उनके अनुसार इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यदि इसकी राई-रत्ती संभावना भी होती, तो कांग्रेस सरकार हाल में एक के बाद एक लगाये गये उचित-अनुचित करों की बजट पूर्व घोषणा न करती। दूसरे, इसकी रही-सही संभावना को कांग्रेस के एकमात्र विपक्षी राज्य के सहयोगी मुख्यमंत्री एम०जी० रामचंद्रन के आकस्मिक निधन ने चौपट कर दिया। उनके कंधों पर सवार हो वह अपनी औकात से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का मंसूबा पाले थे। तमिलनाडु के राजनीतिक शतरंज की गोटें आज बदल चुकी हैं। वर्तमान अस्पष्ट, अनिर्णायक और तनावपूर्ण स्थिति में ऊंट किस करवट बैठेगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे समय मध्यावधि चुनाव का जुआ खेलना कांग्रेस शायद ही पसंद करे।

बहरहाल, कांग्रेस आज तक ऐसे दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है, जहां उसको यह पता नहीं कि वह कब, कैसे और किस ओर अगला कदम बढ़ाये? ऐसे नाजुक समय में एक गलत कदम भी उसके लिए बेहद महंगा साबित होगा। जैसाकि लोकदल-अ महासचिव सुब्रह्मण्यम स्वामी का दावा है, "आज सभी कांग्रेसी व्यग्र और चिंतित हैं। पार्टी में जोश-खरोश का नामोनिशान नहीं है। वे अपनी बुरी तरह से गिरी साख और विश्वसनीयता के कारण चुनावी परिणामों की संभावना से अत्यधिक सशंकित, आतंकित हैं।" अपार पार्टी कोष का मुंह खोल दिये जाने के पश्चात भी उन्हें विजयश्री प्राप्ति की संभावना नितांत धूमिल दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का खुला समर्थन करने में उच्च पदाधिकारी और वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी भी हिचकिचा रहे हैं।

चुनाव आयोग की निंदा: चुनाव-स्थगन के लिए जितनी आलोचना प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हो रही है, उससे कहीं अधिक आलोचना का पात्र चुनाव-आयोग बन गया है। उस पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि उसने सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। आलोचना केवल चुनाव टालने की ही नहीं की जा रही है, बल्कि उन तरीकों और परिस्थितियों पर भी उंगली उठायी जा रही है, जिन्हें आधार बनाकर यह कदम उठाया गया। पूर्व प्रमुख चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने 'माया' से हुई विस्तृत बातचीत के दौरान (देखें बाक्स) चुनाव स्थगन और आयोग के रवैये की घोर भर्त्सना करते हुए इसे सरासर गलत और अनावश्यक करार दिया। कम्युनिस्ट नेता मुकीम अहमद फारूकी का कहना है, "महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों के चुनने के अधिकारों से वंचित न किया जाये।"

मतदान की घोषणा न करने से उठे कुछ विवादों से पिंड छुड़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अन्य विवादास्पद कदम का सहारा लिया है। प्रमुख चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री ने दो पत्रों द्वारा सरकार से चुनाव कानून में व्यापक संशोधन कर दिशा निर्देश सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। जाहिर है कि ऐसा होने पर निर्धारित चुनाव कराने अथवा न कराने के विषय में आयोग वांछित-अवांछित आलोचनाओं से बच निकलेगा। साथ ही चुनाव कार्यक्रम बनाते समय केंद्र व राज्य सरकारों के विचारों को किस सीमा तक महत्व दिया जाये, यह भी स्पष्ट हो जायेगा। किंतु पेरी शास्त्री का यह कदम संविधान द्वारा दिये गये उन विशेष अधिकारों का समर्पण है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग न केवल सरकार से ऊंचा स्थान रखता है, बल्कि कानून से भी ऊपर है। आम आलोचना के अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा काम किन परिस्थितियों में किया होगा, इस बात पर अफवाहों और अटकलबाजियों का बाजार गर्म है।

चुनाव स्थगन संबंधी चर्चाओं में उसकी अवधि एक विशेष मुद्दा है। कांग्रेस का कोई भी नेता यह खुलकर बताने की स्थिति में नही है कि यह चुनाव कब कराये जायेंगे? यह तो सभी मानते हैं कि बीच के समय को कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में लगायेगी, किंतु यदि निर्धारित समय में (जैसे दिल्ली चुनाव एक वर्ष के लिए पुन: टाले गये हैं) कांग्रेस अपने लक्ष्य में असफल होती है, तो उसका अगला कदम क्या होगा? चूंकि दिल्ली चुनाव संबंधी अध्यादेश में इस अवधि को एक-एक कर तीन साल तक बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए विपक्ष, विशेषकर दिल्ली चुनाव में मैदान फतह करने के दावेदार भाजपा का मानना है कि कांग्रेस अपनी तिकड़मबाजी से आगे भी चुनाव टाल सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करेगी। किंतु लोकतांत्रिक प्रणाली में यह कब तक संभव है? जैसा विपक्षी नेता श्री उपेंद्र कहते हैं, "राजीव गांधी अपनी इस 'बला' को अधिक-से-अधिक कुछ दिन ही टाल सकते हैं। आज नहीं, तो कल, उन्हें जनता की अदालत में जाना ही पड़ेगा।"

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

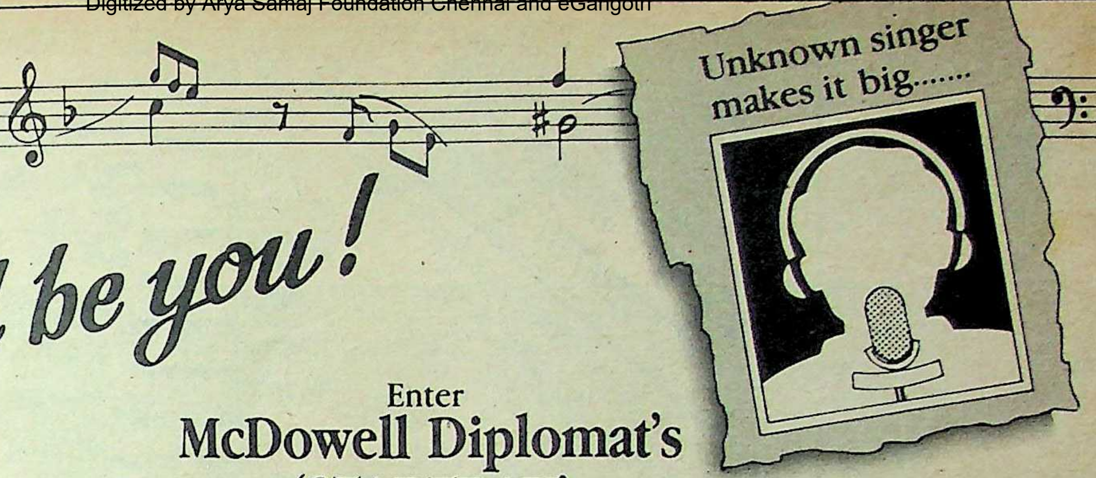
Unknown singer makes it big......

This could be you!

Enter
McDowell Diplomat's 'STARTRAX'
'A music contest
that could create two superstars.'
Organised by

MUSIC INDIA

If you can make music, we can make you a star.

Here's How:

1. Send us an audio cassette with your taped entry, in either of two categories Hindustani Vocal or Instrumental.
2. The cassette must be accompanied by the duly filled entry form, a passport size photo and an entry fee of Rs. 100/- plus 2 self addressed stamped envelopes 5" × 9".
3. Entries close Febraury 20th 1988.

What's Next:

1. These cassettes will be assessed and entries will be narrowed down to the best 20 per region (North, South, East and West).
2. These 20 will perform live at the regional semi-finals to be held in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras.
3. The winners (1st prize per category) of each regional contest will be finalists.
4. The final will be held in Bombay.
5. From the 8 finalists there will be 2 winners (1st prize per category – Rs.25,000) and 2 runners-up (2nd prize per category – Rs. 10,000) PLUS THE OPPORTUNITY TO BECOME A MUSIC INDIA ARTISTE.

Rules and Regulations:

1. Candidates must be 18 years and above.
2. Entry Fee Rs. 100/- (non-refundable) payable to Music India Ltd. A/c 'McDowell Diplomat Startrax Music Talent Contest' by Demand Draft or Postal Order.
3. Only the entry form and passport size photo may accompany the audio cassette.
4. A candidate may send in any number of entries. Each will be treated separately and hence each must be accompanied by a separate entry form, fee and photograph. No entry may exceed 15 minutes.
5. Categories:
   - a) Hindustani Vocal (Ghazals, Geets, Bhajans, Hindi Pop).
   - b) Instrumental (any instrument of the candidate's choice as long as the music is Hindustani).
6. Harmonium, Tabla and Dholak will be the only instruments allowed as accompanying instruments during singing.
7. Participants have to make their own arrangements and bear all expenses for travel, board and lodging.
8. The judges will be eminent personalities from the Music Industry. Their decisions will be final and binding on the participants.
9. The sponsors and organizers reserve the right to call off the contest at any time, accept or reject any entry/entries at their absolute discretion or change the dates and venue without assigning any reason.
10. Employees and their relatives of McDowell & Co. Ltd, Music India Ltd, Ogilvy Benson & Mather and their associate companies are not eligible to enter McDowell's Diplomat 'STARTRAX' Music Talent Contest.

Come on, give this your best shot. It could make all your dreams come true!

Entry Form

1. Name ______________________
2. Address (clearly defining City and State separately) ______________________
3. Date of Birth
4. Category entered ☐ Hindustani Vocal ☐ Instrumental
5. Declaration:

"I have clearly read the rules and regulations of the McDowell's Diplomat 'STARTRAX' Music Talent Contest and do solemnly affirm to abide by the same."
I am enclosing my non-refundable entry fee of Rs. 100/- in the form of DD/Postal Order No. ______ dated ______ alongwith a passport size photograph and two 5" × 9" envelopes.

6. Signature of the applicant. ______________________

Mail all entries to reach before February 20, 1988
McDowell's Diplomat 'STARTRAX' Music Talent Contest
Music India Ltd.,
Sterling Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay – 400 018.

McDowell's
DIPLOMAT
STAR TRAX
Music Talent Contest
Organised by
MUSIC INDIA

OBM 2547 R

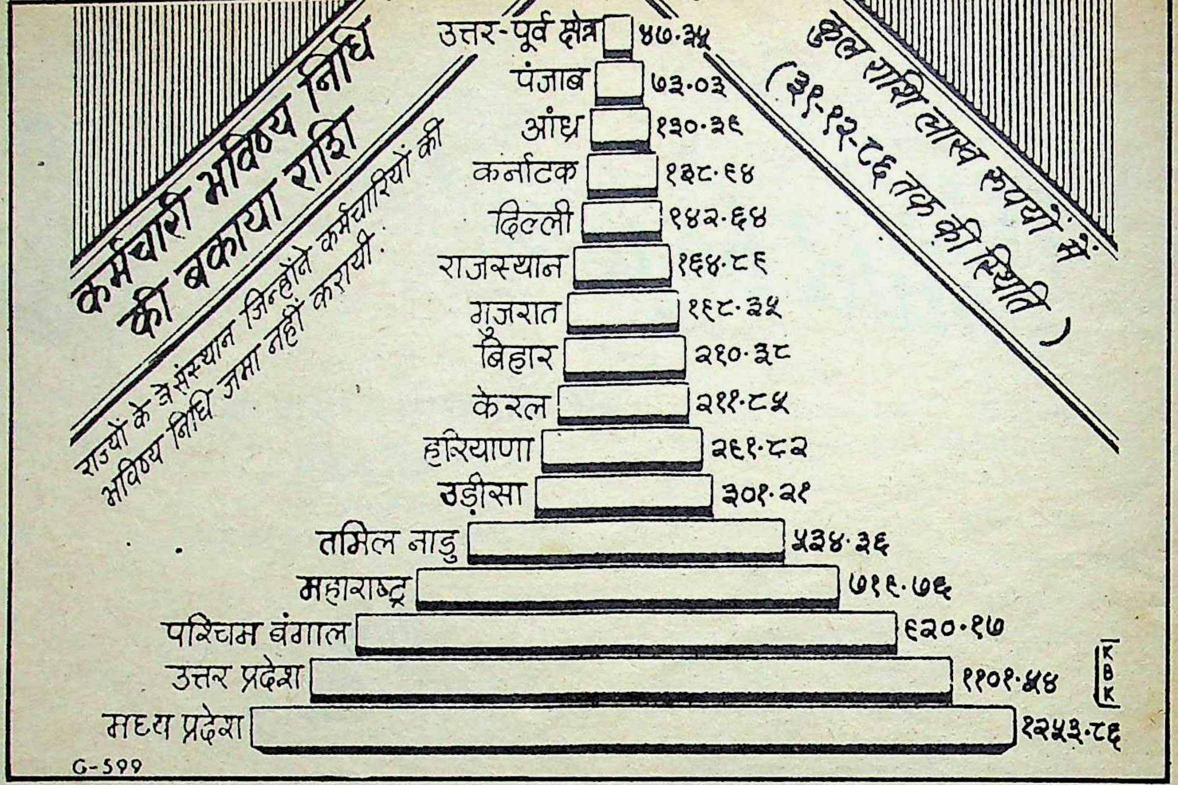

मर्दों का दिल

भारत में ४० साल से कम उम्र के दिल के मरीज पश्चिमी देशों से तीन गुना ज्यादा हैं। एक अनुसंधान के अनुसार औरतों से अधिक मर्दों को दिल के दौरे पड़ते हैं। ४० साल से कम उम्र के मर्दों में यह रोग औरतों के मुकाबले ११ गुना अधिक होता है। जिन युवकों को यह रोग दबोचता है, उनमें से करीब एक तिहाई शराब पीने के आदी होते हैं और ५६ प्रतिशत धूम्रपान के शौकीन।

१९८८ के शुरू में ही एड्स के रोगियों का आंकड़ा ५० हजार पार कर गया है, इनमें २८ हजार रोगियों की मौत हो चुकी है। गत वर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने प्रति सप्ताह एड्स रोगियों के चार सौ मामले सामने आये।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष १९८८ में दुनिया की आर्थिक विकास दर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और विश्व अर्थ व्यवस्था को नये झटके लग सकते हैं।

पूरी दुनिया में वर्ष १९८७ में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर (७.४ प्रतिशत) चीन में रही। इस दौरान विकासशील देशों में राष्ट्रीय उत्पादन की दर २.१ प्रतिशत रही, जबकि १९८६ में यह ३.२ प्रतिशत थी, जबकि विकसित देशों के बाजार में विकास की यह दर २.७ प्रतिशत रही। केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थावाले सोवियत संघ एवं पूर्वी युरोप के अनेक देशों के उत्पादन की विकास दर भी ४.६ प्रतिशत से घटकर १९८७ में ३.२ प्रतिशत रह गयी।

सभी सामानों के अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक में पिछले एक वर्ष में ३१.८ अंकों की वृद्धि हुई। १९७०-७१ के १०० अंकों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक इस साल १२ दिसंबर को ४०९.६ हो गया जो पिछले साल १३ दिसंबर को केवल ३७७.८ था।

पिछले वर्ष अनाज के भावों के सूचकांक में २७.१, अंडा, मास और मछली में १२३.१, दूध और उसके उत्पादन में ३६.९, सब्जी और फल में २५.७, तिलहन सहित दूसरी खाद्य वस्तुओं में ९४.६ अंकों की वृद्धि हुई। सिर्फ मसालों के सूचकांक स्थिर रहे।

त्रिपुरा विधान सभा चुनाव में २०६६४४ नये मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इस प्रदेश में पिछले दशक में ३ लाख ९१ हजार ६३२ मतदाता बढ़े हैं।

राजधानी दिल्ली के राजपथ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध युद्ध स्मारक इंडिया गेट के रखरखाव का कार्य भारत सरकार नहीं करती, बल्कि राष्ट्रमण्डल का ग्रेव्स आयोग करता है। भारत इस आयोग का सदस्य है। उल्लेखनीय है कि इस स्मारक पर उत्तर पूर्व सीमांत प्रांतों में या उससे बाहर लड़ाई के दौरान मारे गये १३ हजार ५२० भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के नाम उत्कीर्ण हैं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ी पांडुलिपियों पर दिल्ली में एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता में १२ लाख, ७६ हजार, ६४१ रुपए पुरस्कारस्वरूप दिये गये।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ३० नवंबर, १९८७ तक १८०.१५ करोड़ रुपए के परिव्यय की १८३ गंगा सफाई योजनाओं को मंजूर किया जा चुका है।

१९८७ में २५ नवंबर तक विभिन्न राज्यों में मलेरिया के ८ लाख, ३२ हजार, ९०४ रोगियों का पता लगाया गया।

विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह के अनुसार चीन की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की भारत-चीन सीमा के पूर्वी इलाके में करीब ९० हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाके पर दावा किया है।

१९८४ से अब तक अमरीका के एक दर्जन नौसैनिक युद्धपोत भारतीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुके हैं।

भारत १९९४ तक पूर्ण स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान बनाने लगेगा। इस योजना पर ५६० करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण पर फैसला देते हुए १९७१ और १९७५ में भारत सरकार द्वारा लागू किये गये आपातकाल को उचित ठहराया है।

भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले १२ महानगरों में २ करोड़ ४० लाख परिवार आवास विहीन हैं। शहरों की निरन्तर बढ़ती आबादी को देखते हुए इस शताब्दी के अंत तक दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या २० तक पहुंच जायेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के०आर० नारायणन के अनुसार भारत में एक-डेढ़ साल के अंदर ही वीडियो कैसेट रिकार्डर व वीडियो कैसेट प्लेयर का निर्माण होने लगेगा। फिलहाल इसके निर्माण की जरूरी तकनीकी जानकारी देश में हासिल नहीं है। इसके लिए जापान,दक्षिणी कोरिया और हालैंड की कंपनियों के मिले-जुले प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

संयोजन : विनोद मिश्र

बोरो कैलेन्डूला*

ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

सूखी और फटी त्वचा का इलाज

Boro calendula*
ANTISEPTIC CREAM

बोरो कैलेन्डूला ऐन्टिसेप्टिक क्रीम।
इसे ज्यादा असरदार बनाती है कुदरत की
अपनी खास औषधियां यानी
कैलेन्डूला और हाईड्रास्टिस के गुणभरे अर्क।
कटने या खरोंच लगने पर आपकी त्वचा की
सुरक्षा करती है। फटे होंटों, फटी एड़ियों और
जलने के छोटे-मोटे घावों का इलाज भी करती है।

**बोरो कैलेन्डूला की सुरक्षा
बारहो महीना त्वचा की रक्षा।**

Mileage/HL/87

* A patent and proprietary homoeopathic medicine of Hahnemann Laboratory

HL का उत्कृष्ट उत्पादन

फिलहाल जयललिता को मात: जानकी रामचंद्रन

जयललिता बनाम जानकी रामचंद्रन

दो महिलाओं का सत्ता संघर्ष

तमिलनाडु में एक घमासान, किंतु रोचक राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक ओर जानकी रामचंद्रन हैं, तो दूसरा मोर्चा जयललिता ने संभाल रखा है। यों तो जानकी एमजीआर की दूसरी पत्नी के रूप में ख्यात हैं और जयललिता एमजीआर की प्रिय फिल्मतारिका एवं अनन्य राजनीतिक शिष्या मानी जाती हैं, लेकिन दोनों का एमजीआर से असली रिश्ता क्या था, इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। बहरहाल दोनों ही जिस तरह एमजीआर के जीतेजी उन पर अपनाएक छत्र अधिकार जमाने के लिए जूझती रही हैं, उसी तरह उनके निधन के बाद उनका उत्तराधिकार हथियाने के लिए भी युद्धरत हैं, यद्यपि पहली बाजी जानकी ने मार ली है, लेकिन प्रतिशोध से भरी जयललिता जल्दी हार मानने वाली नहीं हैं। आखिरी बाजी किसी के भी हाथ लगे, लेकिन इन दोनों महिलाओं के आपस में भिड़ने की नौबत एमजीआर के राजनीतिक खेल और व्यक्तिगत कारणों से आयी है। दोनों महिलाओं की जंग को निकट से देख कर लौटे विजय दत्त की रपट:

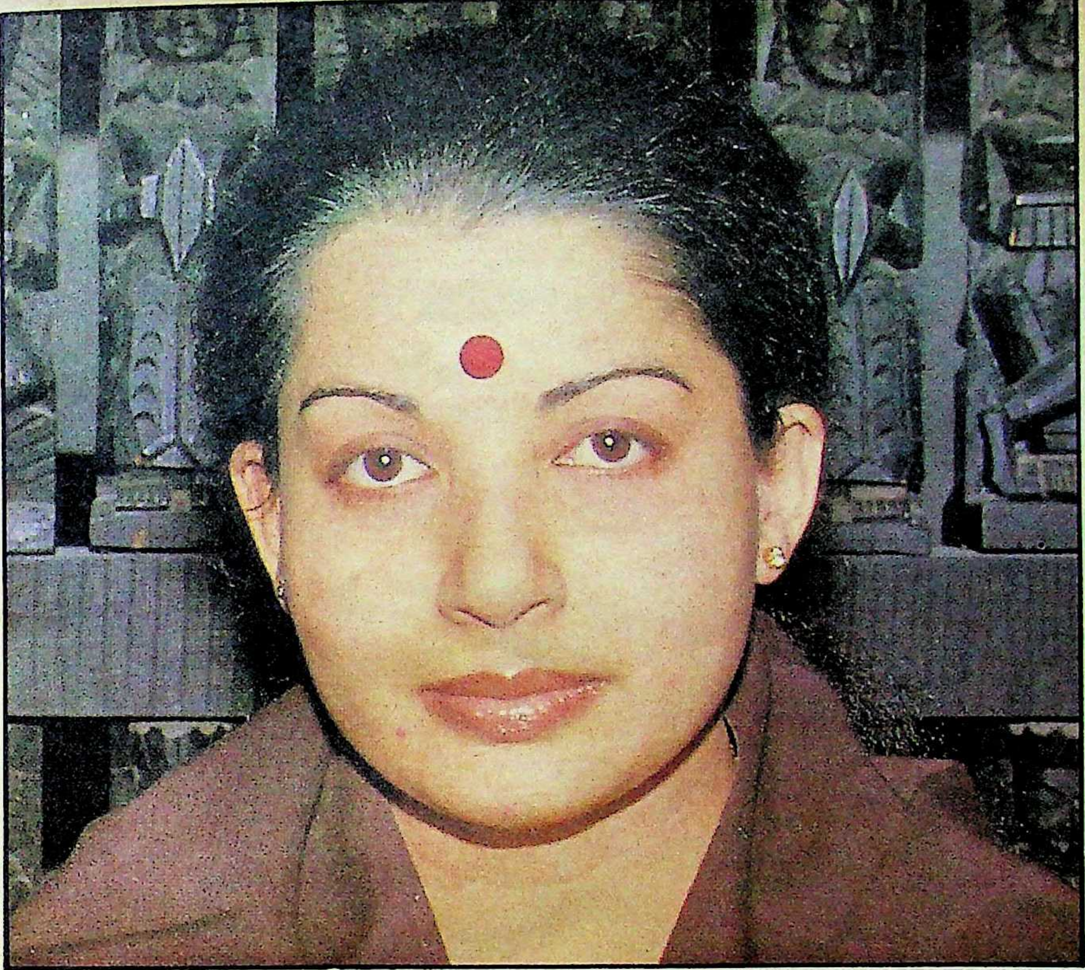

प्रतिशोध के लिए आतुर : जयललिता

एमजीआर के अनुयायी वैकम नारायणी जानकी और जयललिता की भगवान मुरुगा की पहली एवं दूसरी पत्नी—देवयानी और वल्ली के साथ तुलना करते रहे हैं। जाहिर है, उनकी मृत्यु के बाद वी०एन० नेदुनचेझियन या वी०आर० वीरप्पन में से चाहे कोई नेतृत्व करे, अन्नाद्रमुक के लोगों की नजरें 'देवयानी' और 'वल्ली' पर ही टिकी हैं। इस प्रकार मद्रास में जारी सत्ता संघर्ष एक प्रकार से दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है। जहां जानकी ने अपने माथे की बिंदी पोंछ कर ९७ विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री-पद की जायज वारिस बन गयी हैं, वहां जयललिता प्रतिशोध से भरी हैं। वह दावा कर रही हैं कि अन्नाद्रमुक का नेतृत्व उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा एमजीआर ने वादा किया था। उत्तराधिकार का दावा करते हुए उनके माथे पर बिंदी बरकरार ही नहीं है, बल्कि थोड़ी बड़ी भी हो गयी है।

एमजीआर की ये दोनों महिलाएं यद्यपि गैरतमिल मूल की हैं, लेकिन दोनों ने जो खास तमिलपन दिखाया है, उसे स्थानीय लोग अपनी भाषा में 'चक्कलाथई चंडई' (सौतों का कलह) की संज्ञा दे रहे हैं। इस कलह से जानकी-अधीन सरकार और जयललिता-शासित पार्टी को खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि जानकी सरकार के पहले सप्ताह की घटनाओं को देखा जाये, तो इस युद्ध का अंत कड़वा होगा। शायद 'उनके' एमजीआर भी यही चाहते थे कि दोनों को विरासत का सुख न मिले।

एमजीआर की मृत्यु के बाद मद्रास में कुटिल कानाफूसी का बाजार गर्म है और अजीबोगरीब नौटंकी चालू है। एमजीआर की राजनीतिक जायदाद हथियाने के चक्कर में एक दूसरे के चरित्रहनन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा। लेन-देन के मामलों की जब चर्चा होती है, तो करोड़ से नीचे की तो कोई बात ही नहीं करता। संजीदा और जिम्मेदार लोगों की बातों पर यदि आंशिक रूप से भी भरोसा करें, तो भी ऐसा लगता है कि एमजीआर के निधन के बाद १० दिन में १० करोड़ रुपए इधर-से-उधर हुए हैं। आरोपों से किसी को नहीं बख्शा जा रहा—चाहे वह राज्यपाल खुराना हों या कांग्रेस के युवा नेता या दोनों घटकों के विधायक। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि दो औरतों के बीच जंग छिड़ी हुई है जो एमजीआर की निकटता की बिना पर राजनीतिक विरासत पर अपना दावा कर रही हैं। हालांकि कोई स्पष्ट नहीं है कि एमजीआर से दोनों के असली रिश्ते क्या थे—कौन पत्नी थी और कौन मात्र प्रेमिका !

असली दौर : इस जंग का असली दौर तब शुरू हुआ, जब राज्यपाल खुराना ने जानकी को मुख्यमंत्री पद थमा दिया। राज्यपाल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अंतरिम मुख्यमंत्री नेदुनचेझियन को तो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया, किंतु जानकी को बिना बहुमत सिद्ध किये ही सत्ता सौंप दी।

इसी कारण राज्यपाल पर पक्षपात और

एमजीआर की ये दोनों महिलाएं यद्यपि गैरतमिल मूल की हैं, लेकिन दोनों ने जो खास तमिलपन दिखाया है, उसे स्थानीय लोग अपनी भाषा में 'चक्कलथई चंडई' (सौतों का कलह) की संज्ञा दे रहे हैं। इस कलह से जानकी-अधीन सरकार और जयललिता-शासित पार्टी को खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि जानकी सरकार के पहले सप्ताह की घटनाओं को देखा जाये, तो इस युद्ध का अंत कड़वा होगा। शायद 'उनके' एमजीआर भी यही चाहते थे कि दोनों को विरासत का सुख न मिले।

भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अफवाहें हैं कि राज्यपाल की पत्नी इंदिरा खुराना से जानकी मिली थीं और रोते-पीटते हुए उनको अनेक प्रलोभन भी दिये थे। एक अन्य अफवाह के अनुसार वीरप्पन ने खुराना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले जब वीरप्पन पर्यटन मंत्री थे, तब दिल्ली स्थित राज्यपाल-आवास में खुराना के एक बेटे को नाजायज हरकत करते हुए तमिलनाडु के आवासी आयुक्त ने पकड़ लिया था। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद मामला तो रफादफा हो गया था, लेकिन आवासी आयुक्त बालासुब्रह्मण्यम के पास जो चित्र थे, उनको उन्होंने वीरप्पन को थमा दिया था। वैसे तो मामला 'फिल्मी' लगता है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति और फिल्मों में कोई खास विभाजन-रेखा नहीं है।

एमजीआर, जानकी और जयललिता तीनों का ही निकास फिल्मी दुनिया से हुआ है और जैसे फिल्मों में होता है, 'नायक' की मृत्यु के बाद जो शून्य पैदा हुआ है, उसे केवल 'नायिका' ही भर सकती है।

तमिल नियति: जहां तक पति की मृत्यु के बाद पत्नी के उत्तराधिकारी बनने का सवाल है, तीन दशक पहले स्वयं एमजीआर के जन्मस्थान श्रीलंका में ऐसा हो चुका है। लेकिन सिरीमावो भंडारनायके अपने पति की मृत्यु के नौ महीने बाद चुनाव के जरिये गद्दीनशीं हुई थी। जबकि जानकी बिना चुनाव का सामना किये पति के आसन पर जमी हैं। इसीलिए उनके सत्तारोहण की वैधानिकता को जयललिता यह कह कर चुनौती दे रही हैं कि संगठन

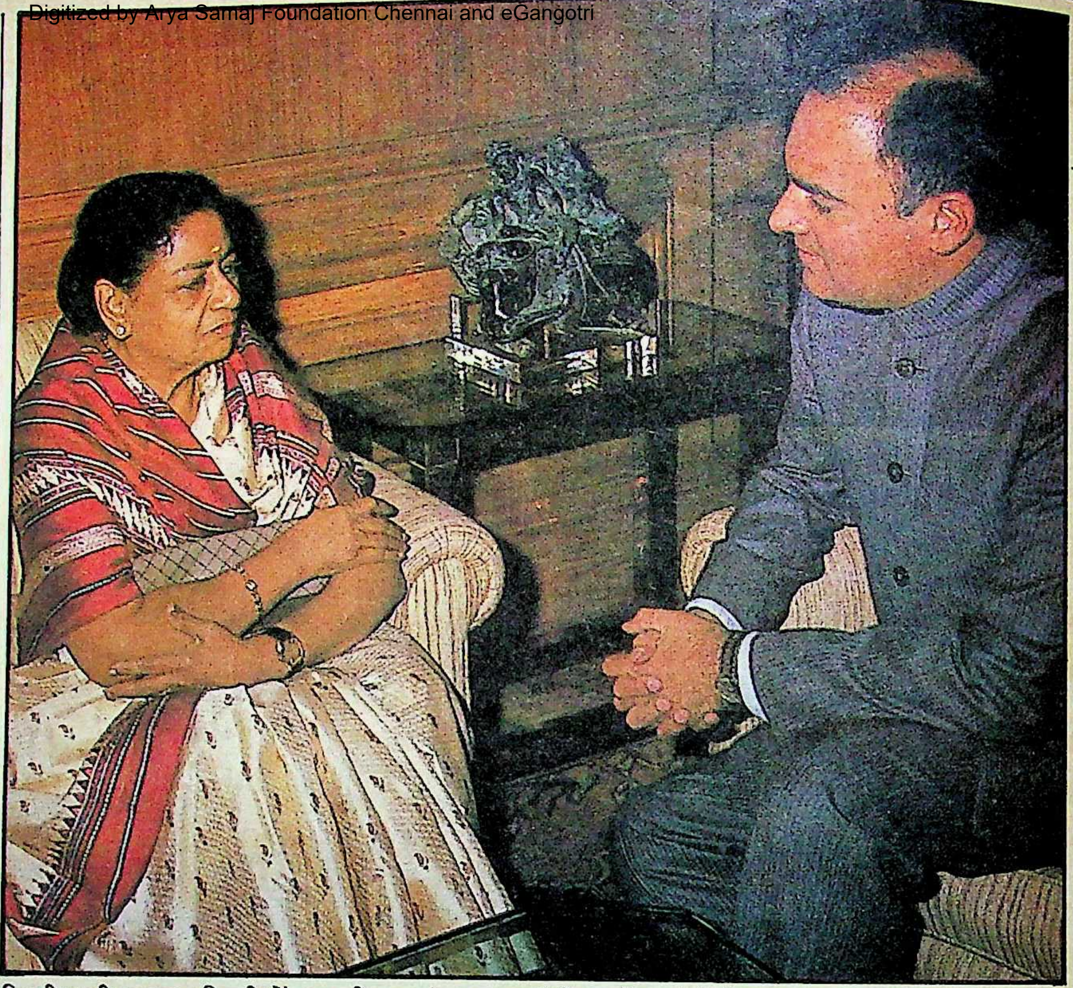

दिल्ली अभी तटस्थ: दिल्ली में जानकी रामचंद्रन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ

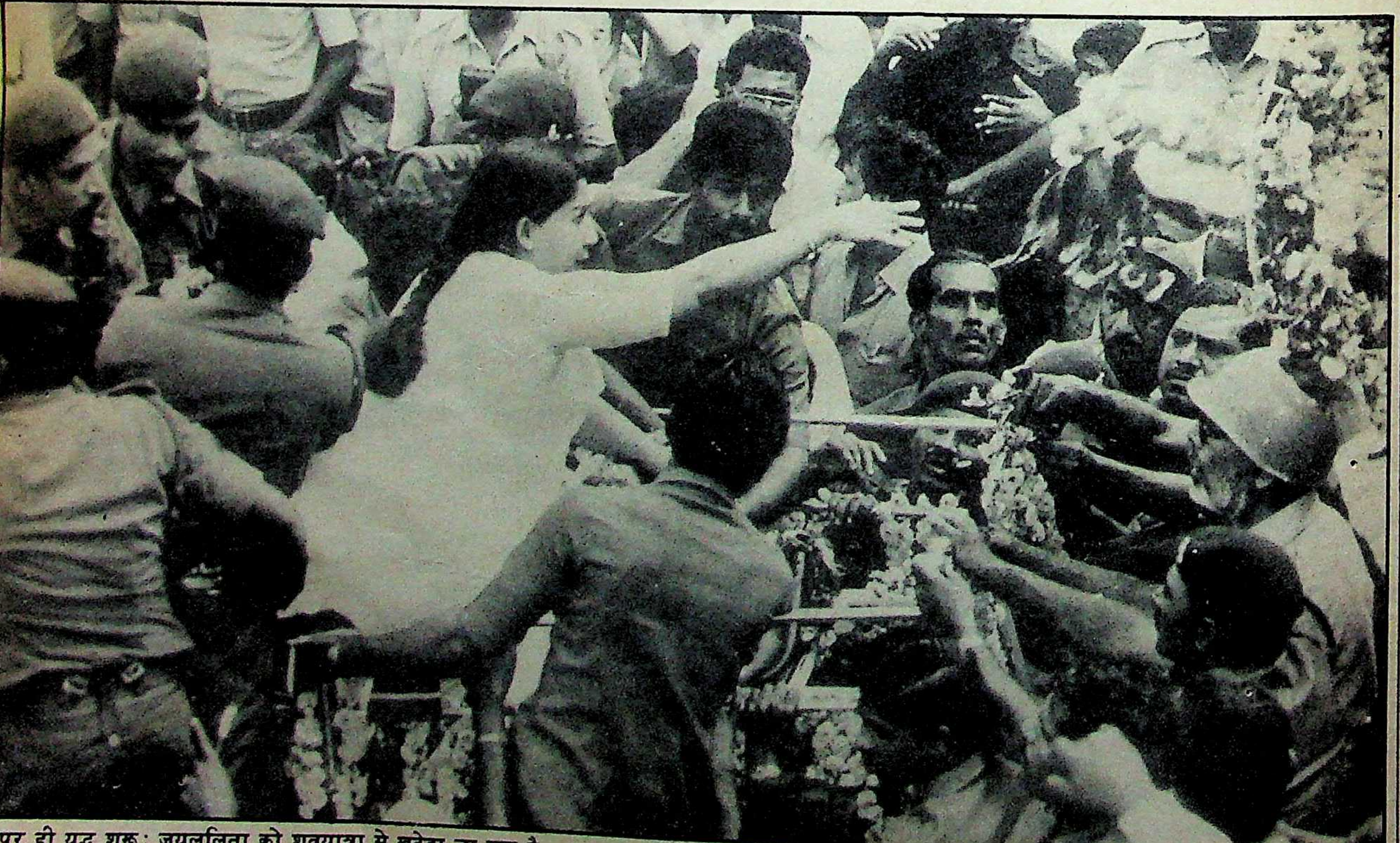

शव पर ही युद्ध शुरू: जयललिता को शवयात्रा से खदेड़ा जा रहा है

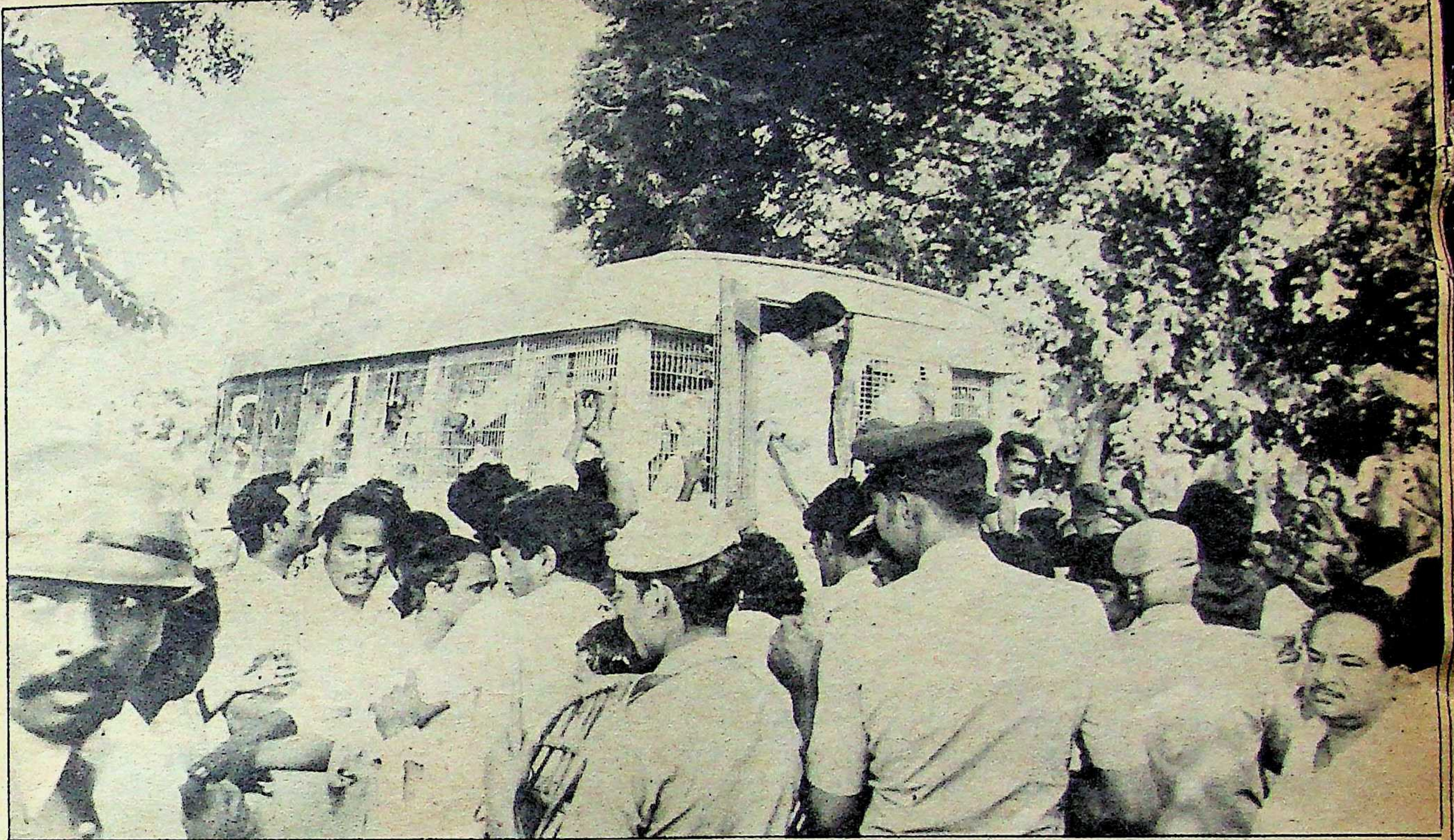

जयललिता का सड़कों पर संघर्ष : गिरफ्तारी देते हुए जयललिता

का बहुमत उनके पास है। एमजीआर के साथ दोनों की वैयक्तिक निकटता के कारण छिड़ी इस जंग के दोनों के अतीत के संबंध में तरह-तरह के किस्से उछल रहे हैं। इन किस्सों में नाजायज संबंधों से लेकर हिंसा और भ्रष्टाचार तक के प्रसंग शामिल हैं।

यदि दोनों में आपसी समझ होती, तो उत्तराधिकार की इस लड़ाई का अंत सुखद और गौरवपूर्ण होता और अन्नाद्रमुक के सारे पुरुष किसी एक की अधीनता चुपचाप स्वीकार कर लेते। ऐसा करते समय न सी०एन० अन्नादुरै और रामास्वामी नायकर जैसे दिग्गज लोगों के चरणों में बैठकर याद किया सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांतों का पाठ आड़े आता और न स्वाभिमान कोई अर्गला लगाता। वे उसी तरह की स्वामिभक्ति दिखाते, जैसी एमजीआर के समय दर्शाया करते थे। एमजीआर ने अपनी देवतुल्य अभयदानी नेता की छवि बना रखी थी, जिससे भावोन्माद से भरा जनसमर्थन उन्हें प्राप्त था। ऐसे नेता का जो भी कृपापात्र होता है, उसका भी वैसा ही जनस्नेह मिलना अस्वाभाविक नहीं है। यही कारण हैं कि कर्नाटक की कन्नड अयंगर जयललिता और केरल की नायर जानकी के वी०एन० नेदुनचेझियन और आर०एम० वीरप्पन जैसे अन्नादुरै के अनुयायी नेता अनुगामी बने हुए हैं। जाहिर है एमजीआर का राजनीतिक खेल ही कुछ ऐसा था कि तमिलों के लिए दोनों महिलाओं पर निर्भर होने के बजाय कोई चारा नहीं है।

> राजीव गांधी से जानकी की दिल्ली में मुलाकात के बाद जयललिता ने चार बार कोशिश की कि उन्हें राजीव गांधी से मुलाकात का समय दिया जाये, लेकिन प्रधानमंत्री के सचिवालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जानकी इस समय ताल नहीं ठोंक रही हैं। वह यह दिखाना चाहती हैं कि वह शांति से शासन चलाना चाहती हैं, जबकि अल्पमत में होते हुए भी जयललिता-खेमा संकट खड़ा करने पर आमादा है।

लेकिन दोनों के टकराव ने अब अन्नाद्रमुक के भविष्य पर सवालिया निशान टांग दिया है। जहां जानकी ने गद्दी संभाल कर दूर खड़े हो कर नेदुनचेझियन से जूझने के लिए अपने लोगों को आगे कर दिया है, वहीं प्रतिशोध से आप्लावित जयललिता सड़कों पर लड़ने के लिए उतर आयी हैं। हालांकि वह अपनी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए केंद्र की सकारात्मक प्रतिक्रिया से वंचित हैं।

कहा जाता है राजीव गांधी से जानकी की दिल्ली में मुलाकात के बाद जयललिता ने चार बार कोशिश की कि उन्हें राजीव गांधी से मुलाकात का समय दिया जाये, लेकिन प्रधानमंत्री के सचिवालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जानकी इस समय ताल नहीं ठोंक रही हैं। वह यह दिखाना चाहती हैं कि वह शांति से शासन चलाना चाहती हैं, जबकि अल्पमत में होते हुए भी जयललिता-खेमा संकट खड़ा करने पर आमादा है। जानकी-धड़े द्वारा १२ जनवरी को अन्नाद्रमुक की मद्रास स्थित मुख्यालय में एक बैठक बुलायी गयी थी। इसके बाद जयललिता के गुट ने भी उसी स्थान पर एक बैठक करने की घोषणा कर दी। जानकी ने तुरंत यह कहते हुए बैठक स्थगित कर दी कि वह टकराव नहीं चाहतीं। लेकिन उनकी पुलिस ने जयललिता और उनके अनुयायियों को मुख्यालय में प्रवेश और बैठक करने से रोक दिया।

इसका परिणाम हुआ लाठी चार्ज, जिसमें जयललिता और नेदुनचेझियन सहित एमजीआर

[illegible] के अन्य मंत्री गिरफ्तार हुए। जयललिता तब तक मुख्यालय से नहीं हटीं, जब तक उन्हें पुलिस वाहन में नहीं धकेला गया। अफवाह फैली कि जयललिता लाठी चार्ज में घायल हो गयी हैं। देखते-ही-देखते भीड़ उनके उस 'पायस गार्डन हाउस' के सामने इकट्ठी हो गयी, जो एमजीआर द्वारा उन्हें दिया गया बताया जाता है।

लायड्स रोड स्थित पार्टी मुख्यालय का भवन पहले जानकी के नाम था, लेकिन इलाज के लिए अमरीका जाने के कुछ महीने पहले एमजीआर ने जयललिता के आग्रह पर इसे अन्नाद्रमुक के नाम स्थानांतरित कर दिया था। जयललिता का यह भी कहना है कि उसी समय एमजीआर ने अपनी मां की तस्वीर जयललिता के हाथ थमा कर यह शपथ दिलायी थी कि वह कभी राजनीति या अन्नाद्रमुक को नहीं छोड़ेंगी। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमजीआर के समय जो महत्व, अधिकार और नेतृत्व जयललिता को मिला हुआ था, उससे वह आज वंचित होने के कारण कितनी क्रुद्ध होंगी। उस समय उनका रुतबा यह था कि जिस जनसभा के मंच पर वह होती थीं, उस पर विधायकों और मंत्रियों तक को बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। वह अपेक्षा रखती थीं कि उनकी कार का

एक गुट के नेता: शिवाजी गणेशन

शिवाजी गणेशन लोकप्रिय तो हैं और उनके पास लगभग छह विधायक भी हैं, लेकिन वह केंद्रीय नेताओं से ज्यादा खुश नहीं—और फिर उनमें राजनीतिक कूवत भी नहीं है। इनका खेमा तमिलनाडु इंका के भूतपूर्व अध्यक्ष के अधीन है, लेकिन वह आलाकमान के व्यवहार से खफा हैं।

जानकी रामचंद्रन

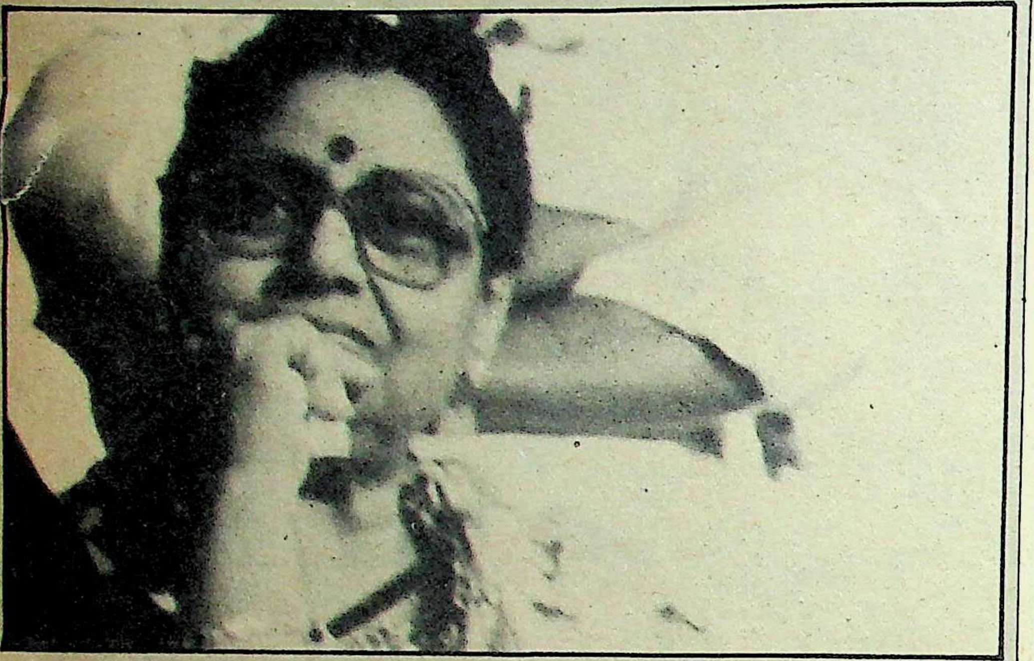

श्रीमती जानकी रामचंद्रन का जन्म केरल के कोट्टायम जिले के वायकम गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम नारायणी जानकी अम्मा है। आजादी की लड़ाई के दौरान १९३० के दशक में वायकम काफी प्रसिद्ध हुआ था। यहां पर महात्मा गांधी ने हरिजनों का नेतृत्व करके शिव मंदिर में प्रवेश किया था। इसी के बाद ट्रेवेनकोर के महाराजा ने १९३४ में मंदिर में किसी भी जाति के प्रवेश का नियम बनाया था।

वहां जारी मातृ सत्तात्मक प्रथा के अनुसार नारायणी जानकी राजगोपाला अय्यर को, जो कि कहा जाता है जानकी के पिता हैं, घर ले आयी थीं। अय्यर तंजावुर जिले के कुंबाकोनम गांव के रहने वाले थे। नारायणी और अय्यर का संबंध ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसी के साथ ही जानकी के बुरे दिन आ गये। जब वह तीसरी कक्षा में थी, तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। दस साल की उम्र में जानकी को उसके पिता अय्यर ने स्वीकार कर लिया और जानकी तंजावुर आ गयी। यहीं उसने नृत्य और संगीत सीखा। ४० के दशक में उसने कुछ फिल्मों में छोटे-छोटे रोल भी किये। एमजीआर की जिंदगी में जानकी का प्रवेश फिल्मों के जरिये हुआ। उनको फिल्म 'मरुथानट्ट इल्लावरसी' के लिए जानकी की फोटो दिखायी गयी। फोटो देखकर उन्हें अपनी दूसरी पत्नी की याद आ गयी जो उस समय टीबी रोग से आक्रांत थी। जानकी उस समय फिल्म इंडस्ट्री के एक मामूली मुलाजिम गणपति भट्ट की पत्नी थी, लेकिन एमजीआर जानकी पर मोहित थे। इसलिए जानकी को अपने घर ले आये। बगैर शादी के उन्होंने १८ साल जानकी के साथ गुजारे और बाद में इस रिश्ते को कानूनी रूप मिला। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी जांनकी को सरकार या अन्नाद्रमुक पार्टी में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाने दी। १९८४ में बीमारी के कारण एमजीआर जानकी पर बिलकुल आश्रित हो गये। तब बहुत से लोगों ने उनके जरिये सरकारी फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की। जब १९८६ के मध्य में एमजीआर को इस बात की सूचना मिली, तो उन्होंने स्थानीय अखबारों में अपने दस्तखतसुदा विज्ञापन छपवाये कि सरकारी अधिकारी या जनता जानकी द्वारा मिले किसी भी आदेश को न मानें। लेकिन जैसे-जैसे वह कमजोर होते गये, वैसे-वैसे जानकी का महत्व बढ़ता गया। वह एक मजबूत राजनीतिक दावेदार के रूप में उभरने लगीं। इसी समय उन्हें राजनीतिक समीकरणों को समझने का मौका मिला।

अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिन लोगों से वह घिरी हुई हैं, वे उन्हें बदनाम न कर दें। कहा जाता है कि पूर्व कांग्रेसी नेता ई०बी०के० संपत की पत्नी सुलोचना संपत और योजना आयोग के उपाध्यक्ष पौलार मुरुथू स्वामी की दूसरी पत्नी, फिल्म अभिनेता एवं पूर्व सांसद की परित्यक्ता विजय कुमारी से जानकी के निकट संबंध हैं। राजनीति में नौसिखिया होने के कारण जानकी अन्नाद्रमुक के उन सदस्यों की कठपुतली बनने के लिएं मजबूर हो सकती हैं जो भ्रष्टाचार से महिमामंडित होने में विश्वास करते हैं।

■

दरवाजा कलेक्टर और एस०पी० खोलें और ऐसा उन्होंने करवाया भी। उनकी आज्ञा से विशाल रैलियों का आयोजन होता था, जिनके लिए अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता छोटे व्यापारियों का सरेआम दोहन करते थे। जयललिता के हौसले इतने निरंकुश थे कि उन्होंने अनेक बार वरिष्ठ सरकारी अफसरों को झाड़ा, प्रेस कांफ्रेंस में सीधे सवाल पूछने के लिए पत्रकारों को धमकी दी, सार्वजनिक स्थानों पर हंगामे खड़े किये—इस सबके कारण उसी एमजीआर की हेठी हुई, जिन्होंने उनको राजनीति में दीक्षित किया था। अकसर वह कहती थीं कि वह राजनीति में पी०एच०-डी हैं, जबकि अन्नाद्रमुक के दूसरे लोग क ख ग भी ठीक से नहीं सीख पाये हैं। लेकिन जब वह राज्यसभा की सदस्य बन गयीं, तो एमजीआर को शक हुआ कि वह कांग्रेस-इ के-खासकर राजीव गांधी के—काफी करीब होती जा रही हैं। उस समय एमजीआर अमरीका में बीमार पड़े थे और उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित लौट सकेंगे।

कांग्रेस-इ जयललिता को अन्नाद्रमुक का नेतृत्व संभालने के लिए इसलिए शह दे रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ आकर्षित

जानकी के सूत्रधार: नेदुनचेझियन

वी०आर० नेदुनचेझियन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके प्रभाव को स्वीकारा है और एक तरह से अपने गुट की कमान उन्हें सौंप दी है, किंतु हठधर्मी व गुस्सा, जो संभवतः उन्हें अपने नेता से विरासत में मिला है, उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।

जयललिता

जयललिता मैसूर के एक अयंगर ब्राह्मण परिवार की संतान हैं। पहली बार मां संध्या ने जब उन्हें मंच पर प्रस्तुत किया था, तब वह छह वर्ष की थीं। यूनाइटेड एमेच्योर आर्टिस्ट नामक इस थियेटर ग्रुप में तब चो रामास्वामी भी शामिल थे। उन्होंने १९५७ के लगभग जब अभिनय आरंभ किया तो उस समय जयललिता करीब ७ साल की थीं। किशोरावस्था में ही जयललिता उन तमाम कठिनाइयों से वाकिफ हो गयी थीं, जिनका सामना किसी भी सुंदर, युवती को फिल्म जगत में करना पड़ता है। जयललिता के परिवार के लिए ग्लैमर व धन की चकाचौंध की अहमियत शिक्षा से ज्यादा थी, जबकि जयललिता पढ़ना चाहती थीं। लेकिन हाईस्कूल से आगे वह नहीं पढ़ पायीं। साठ के दशक के उत्तरार्ध में उनकी भेंट एमजीआर से हुई और वह उनकी लोकप्रियता से अत्यधिक प्रभावित हुईं। हालांकि फिल्म जगत के आलोचक उन्हें अली (नपुंसक) कहते थे, परंतु महिलाओं में उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल थी।

मां के देहांत के बाद जयललिता फिल्म जगत में पूर्ण रूप से एमजीआर पर निर्भर हो गयीं। एमजीआर अपने जीवन में आनेवाली तमाम महिलाओं में सबसे अधिक जयललिता को चाहते थे। इसी कारण आर०एम० वीरप्पन को इससे जानकी के लिए खतरा दिखायी दिया। उन्होंने एमजीआर के साथ जयललिता की इस निकटता का विरोध किया और उनकी लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र तक जा पहुंची। जब एमजीआर जयललिता से क्रुद्ध होते, तो यह वीरप्पन के लिए खुशी की बात होती, किंतु यह खुशी तब क्षोभ में बदल जाती जब एमजीआर व जयललिता आपस में फिर मिल जाते। इस नाजुक रिश्ते में ये भावात्मक उतार-चढ़ाव एमजीआर के ईष्यालु स्वभाव व अहं के कारण आते रहते थे। अपनी अन्य महिला मित्रों के दूसरों के साथ संबंध एमजीआर को इतना विचलित नहीं करते थे, जितना जयललिता का किसी दूसरे के प्रति आकर्षित होना। यदि उनका बस चलता, तो वह उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते। शायद इसी भय से जयललिता सत्तर के दशक के मध्य में एमजीआर से कुछ दूर चली गयीं। कहा जाता है कि इसी दौरान वह शोबन बाबू के प्रति आकर्षित हुईं। वह विवाह भी करना चाहती थीं, किंतु शोबन बाबू अपनी पहली पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह कशमकश चल ही रही थी कि एमजीआर का पुनर्प्रवेश हुआ। बढ़ती उम्र के चलते और व्यक्तिगत व राजनीतिक जीवन में उन्हें कदाचित पुनः आकर्षण, आश्वासन और आत्मबल की जरूरत थी।

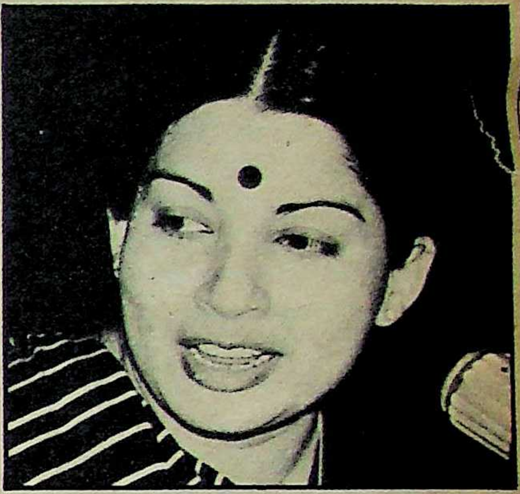

जयललिता को अन्नाद्रमुक में शामिल किया गया और एमजीआर ने उन्हें 'वोट बटोरने वाली' के रूप में इस्तेमाल करने की सभी कोशिशें कीं। १९८४ में एमजीआर को इलाज के लिए एयर इंडिया के विमान से न्यूयार्क ले जाया गया और इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गयी। जयललिता ने चुनाव अभियान की बागडोर संभाली और विधानसभा चुनाव जीत कर दिखा दिया। हालांकि इन चुनावों में सहानुभूति की लहर का भी बड़ा भारी योगदान था।

जब वह अत्यधिक लोकप्रिय हो गयीं, तो एमजीआर पुनः प्रकट हुए और उन्हें एक बार फिर किनारे कर दिया। उन पर कांग्रेस-इ का डबल एजेंट होने का आरोप तक लगाया गया।

अंतिम तीन वर्षों में वह एमजीआर द्वारा बहुत पीड़ित-प्रताड़ित की गयीं। अब उनके निधन के बाद देखना है कि बाजी किसके हाथ लगती है। वी०आर० नेदुनचेझियन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके प्रभाव को स्वीकारा है और एक तरह से अपने गुट की कमान उन्हें सौंप दी है, किंतु हठधर्मी व गुस्सा, जो संभवतः उन्हें अपने नेता से विरासत में मिला है, उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।

पार्टी के एक कार्यकर्ता, जिसने जयललिता को एक जनवरी को पार्टी आफिस के बाहर पुलिस अधिकारियों से बहस करते हुए देखा है, का कहना है, "उन्हें कम उम्र से ही पुरुषों की ताकत का सामना करना पड़ा है और आज वह जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरे तंत्र से लड़ना पड़ा। यदि वह मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तो फिर उन्हें वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जयललिता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर की औरत को कैसे ढालती हैं।" ■

हुई थी, जबकि एमजीआर अमरीका में बीमार पड़े थे। एमजीआर लौटे, तो उनको जयललिता और कांग्रेस के निकट संबंध नहीं भाये, परिणाम-स्वरूप उन्होंने जयललिता को सबक सिखाने की ठान ली। जयललिता से कहा गया कि वह राज्यसभा के सत्रों में ज्यादा उपस्थित न रहें। इसके साथ दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में एमजीआर के बगलवाला सुइट सील कर दिया। जयललिता को एक बार नववर्ष की संध्या एक प्रकार से गलियों में गुजारनी पड़ी।

लेकिन वह जल्दी ही फिर उभर आयीं और फिर से पार्टी की प्रचार सचिव बन गयीं। लेकिन इस बीच एमजीआर की जनसभाओं में निरंतर दिखायी देने लगीं एवं मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों तथा एमजीआर के बीच संपर्क-सूत्र की भूमिका निभाने लग गयीं।

बीमार होने के बाद: दोनों महिलाओं ने देवयानी और वल्ली का रूप तब धारण किया, जब एमजीआर भगवान मुरुगा की स्थिति से वंचित हो गये। एमजीआर की १९८४ से देखरेख कर रहे एक चिकित्सक के अनुसार एमजीआर अपनी मौत के छह महीने पहले से सभी संबंधियों, अंतरंगों से नफरत करने लगे थे। इसका प्रमुख कारण था कि वह अपनी गंभीर बीमारी की वजह से बिस्तर से लग गये थे और वह सब करने में अपने को पूर्णतया असफल पा रहे थे जो अब तक करते रहे थे।

नितांत असहाय, मूक साक्षी बनकर पत्नी जानकी और अन्य सहयोगियों—जयललिता, नेदुनचेझियन, एस० रामचंद्रन, आर०एम० वीरप्पन को वह अपनी मेहनत से लगाये पेड़ का फल खाते देख रहे थे। अपने नजदीकी लोगों को अत्यंत खुशहाल और शक्तिशाली देखकर वह कटुता से भर उठते थे। उस समय एमजीआर का यही असली रूप था—असुरक्षित, भयभीत।

पिछले तीन वर्षों में उन्हें इस बात का पूरा अहसास हो गया था कि उनका अंत निकट है। फिर भी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो जनता पर उनका ऐसा जादू था कि वह सहज ही उस व्यक्ति को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेती।

इसके बावजूद उन्होंने किया इसका उलटा। यदि किसी भी नामजद उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा, तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाये, जिससे इसकी संभावना पूर्णतया समाप्त हो जाये। यही कारण है कि उन्होंने जयललिता, वीरप्पन तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों को पुचकारने और दुत्कारने का खेल जारी रखा। उन्हें पहले कुछ देने और बाद में छीन लेने में एक अजीब खुशी हासिल होती थी।

कहा जाता है कि मृत्यु के १५ दिन पूर्व यकायक उन्होंने टेलीफोनों-ट्रंककालों द्वारा समस्त अन्नाद्रमुक सांसदों-विधायकों से कहा कि वे जयललिता से संपर्क तोड़ दें। यहां तक कि उनसे बातचीत करने की भी सख्त मनाही की। किंतु फिर मृत्यु के एक हफ्ते पहले वह सुबह ११:५० बजे पार्टी कार्यालय आये और उन्होंने जयललिता व अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ दोपहर डेढ़ बजे तक

कांग्रेस की भूमिका

एक प्रसिद्ध लोककथा है: दो बिल्लियों का एक रोटी को लेकर झगड़ा हो गया, तो वे फैसले के लिए बंदर के पास गयीं। बिल्लियां फैसले का इंतजार करती ही रह गयीं कि बंदर सारी रोटी चट कर गया। कोई ताज्जुब नहीं यदि जानकी रामचंद्रन और जयललिता के झगड़े में बंदर की भूमिका कांग्रेस-इ निभाये। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत यह है कि उसमें आपस में गुटबंदी है और वहां का नेतृत्व भी माशाअल्लाह है। इसीलिए राजीव गांधी दोनों महिलाओं को संधि करने का मशविरा दे रहे हैं।

राजीव गांधी का अहम मकसद मद्रास में ऐसी सरकार की स्थापना है, जिसके साथ जनमत हो और जो श्रीलंका समझौते का समर्थन करे। इसी कारण उनकी राष्ट्रपति शासन लागू करने में रुचि नहीं है, क्योंकि यदि राज्यपाल समझौते के पक्ष में बयान जारी करता भी रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा विकल्प उनके पास है, अपने ६४ विधायकों के जरिये वह जानकी या जयललिता का समर्थन करके सरकार चलवायें। लेकिन यह भी निरापद नहीं, क्योंकि इससे विरोधी धड़ा अतिवादी हो कर समझौते का तगड़ा विरोध करने लगेगा और यह भी संभव है कि वह करुणानिधि की गोद में जा बैठे, जिसे केंद्र कतई नहीं चाहता। जानकी के धड़े में तो समझौता-विरोधी लोग ज्यादा हैं और वे उग्र भी हैं। दूसरी ओर, जयललिता के पास जो २७ विधायक हैं, वे कब तक उनका साथ देंगे, कोई पता नहीं। उनको जिस तरह मद्रास से बाहर घेर कर रखा गया है, उसी से उनकी वफादारी संदिग्ध होना जाहिर हो जाती है।

हालांकि जानकी ने भी अपने ९७ विधायकों को शुरू में महाबलिपुरम में रोक कर रखा था, लेकिन बाद में उनकी गतिविधियां निर्बंध कर दी गयीं। पोंगल के दिन अधिकांश विधायक अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस-इ जानकी-सरकार के संबंध में काफी सतर्कता बरत रही है। उसका खयाल है कि यदि जयललिता के दावे के अनुसार पार्टी कैडर उनके साथ, है, तो जानकी की सरकार अपने आप ढह जायेगी। इसलिए वह नहीं चाहती कि एमजीआर की विधवा द्वारा संचालित सरकार को बर्खास्त कर या गिरा कर तमिलों का कोपभाजन बने।

मुसीबत की जड़: लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुसीबत की जड़ तो यह है कि कांग्रेस-इ की प्रदेश शाखा तीन-तेरह है। जी०के० मूपनार के हाथों में प्रदेश की लगाम है, लेकिन वह जननेता नहीं। शिवाजी गणेशन लोकप्रिय तो हैं और उनके पास लगभग छह विधायक भी हैं, लेकिन वह केंद्रीय नेताओं से ज्यादा खुश नहीं—और फिर उनमें राजनीतिक कूवत भी नहीं है। इनका खेमा तमिलनाडु इंका के भूतपूर्व अध्यक्ष के अधीन है, लेकिन वह आलाकमान के व्यवहार से खफा हैं। वह मूपनार के घोर विरोधी हैं। इस प्रकार तमिलनाडु में कांग्रेस का घर तितर-बितर है। यहां तक कि विभिन्न गुट आपस में लड़ते हुए आलाकमान को भी बुरा-भला सुनाने से बाज नहीं आते।

गणेशन के फैन-क्लब के लोग उड़ाते रहे हैं कि मूपनार जब राजीव गांधी से मिलने गये थे, तो अपने साथ तमिल फिल्मों में काम करने वाली अंबिका और राधा दोनों मलयाली बहनों को लेकर गये थे, जबकि मूपनार का खेमा यह आरोप शिवाजी गणेशन पर लगा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश युवा कांग्रेस-इ के नेताओं ने जानकी से वायदा किया है कि वे अपनी पार्टी के १२ विधायकों का समर्थन दिला देंगे। सूत्रों का दावा है कि यह समर्थन एक करोड़ रुपए देकर हासिल किया जा रहा है। कुछ कांग्रेसी तो यह कह रहे हैं कि यदि केंद्र ने जयललिता को समर्थन दिया, तो स्वयं राजीव गांधी की बदनामी होगी। इसका कारण मद्रास में जयललिता ने इन नेताओं के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां की हैं।

इन आरोपों में चाहे दम भले ही न हो, लेकिन ऐसी हालत में राजीव गांधी चुनाव थोप कर राज्य में सत्ता हथियाने की उम्मीद नहीं कर सकते।

१९८४ के चुनाव में जब एमजीआर न्यूयार्क के एक अस्पताल में बुरी तरह बीमार पड़े थे, तो कांग्रेस के अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करके ६४ सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन अन्नाद्रमुक को १३२ सीटें मिल जाने के कारण सत्ता में हिस्सा पाने का कांग्रेसी सपना पूरा नहीं हो सका था। हालांकि एमजीआर केंद्र के प्रति कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा वफादारी प्रदर्शित करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस-इ को सत्ता में हिस्सेदारी की इजाजत नहीं दी। एमजीआर के निधन के बाद राजीव गांधी को उम्मीद थी कि अन्नाद्रमुक दोनों महिलाओं को आधा-आधा समर्थन देगा। लेकिन जानकी ने २२३ विधायकों के सदन में ९७ विधायकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि द्रमुक के १४ विधायक इस समय निलंबित हैं। इसलिए बड़े भाई की भूमिका निभाने की योजना धरी-की-धरी रह गयी। इसलिए जब तक अन्नाद्रमुक अपनी फूट का शिकार होकर खुद नही चरमरा जाती या दोयम दर्जे की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं पहुंच जाती, तब तक कांग्रेस-इ को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

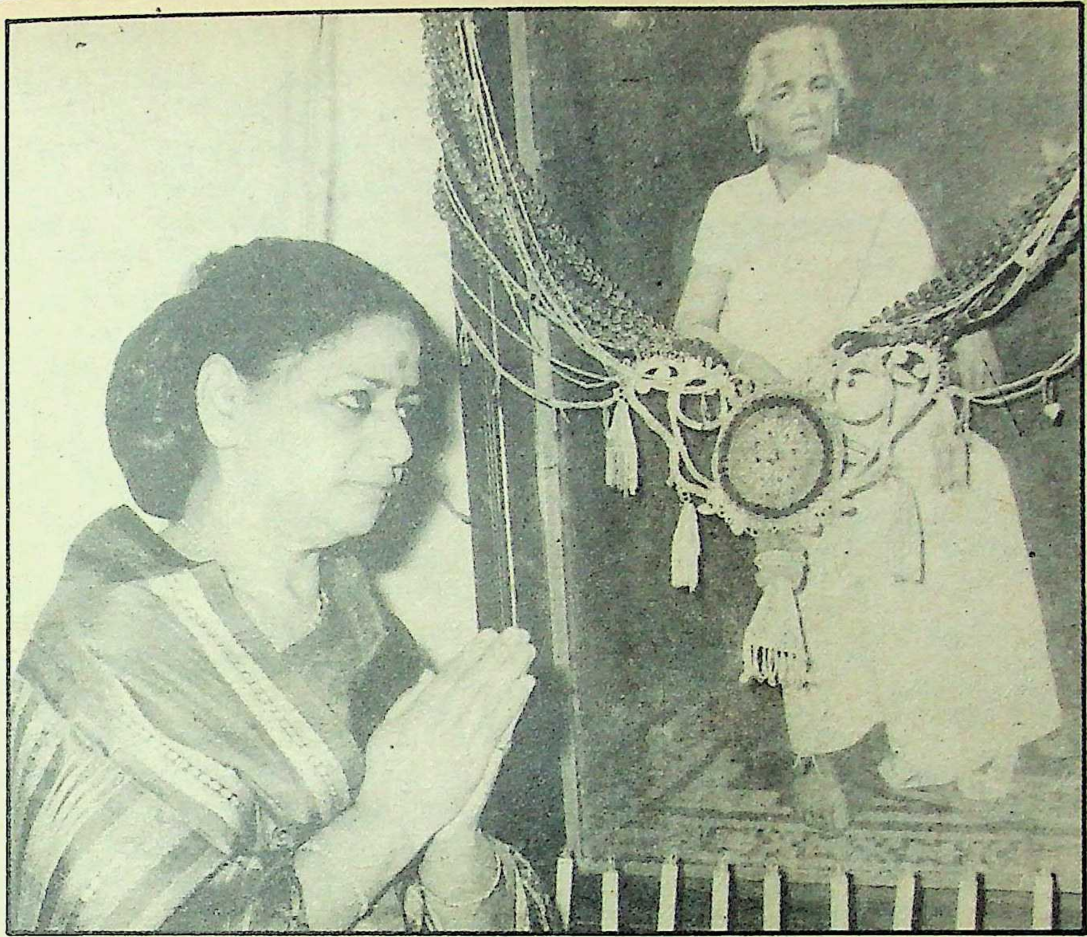

सद्गृहिणी की छवि की चिंता : जानकी रामचंद्रन

एमजीआर-प्रिया : फिल्म 'तन्नीपेरवी' में एमजीआर के साथ जयललिता

बातचीत की। २२ दिसबर को पुनः उन्होंने पार्टी उपसचिव एस० राघवानंदम को पार्टी मुख्यालय में जयललिता के कक्ष में लगे टेलीफोन को तुरंत कटवा देने का फरमान जारी कर दिया।

इसी प्रकार ८ महीने पूर्व तत्कालीन वरिष्ठ पार्टी उप महासचिव व पूर्व मंत्री डा० एच०वी० हांडे को एमजीआर के सुरक्षा-अमले की ओर से आदेश मिले थे कि जयललिता का टेलीफोन काट दिया जाये। डा० हांडे ने इसकी पुष्टि करनी चाही, तो एमजीआर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, "मैंने टेलीफोन तुरंत काट देने को कहा था और अभी तक पूछतांछ ही की जा रही है।" फिर छह हफ्ते बाद डा० हांडे को आदेश हुआ कि जयललिता की टेलीफोन लाइन चालू कर दी जाये।

और-तो-और पत्नी जानकी को भी एमजीआर की मनोरोगात्मक सनक का निशाना बनना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने एक बार सभी तमिल अखबारों में विज्ञापन छपवाया कि जानकी अथवा उनके किसी अन्य रिश्तेदार का अन्नाद्रमुक या सरकार से कुछ लेना-देना नहीं है। इससे जानकी की सांसत और तौहीन की कल्पना की जा सकती है। वीरप्पन भी इससे अछूते नहीं रहे—एक दिन मंत्री बनाये जाते, दूसरे दिन निकाले जाते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और तमिलनाडु की राजनीति के ज्ञाता न्यायमूर्ति वी०आर० कृष्ण अय्यर दो महिलाओं के बीच संघर्ष को एक और ही दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्होंने माया से कहा, "इस समय हम जो कुछ देख रहे हैं, वह राज्य में एक स्वस्थ राजनीति का परिचायक है। जब तक एमजीआर जिंदा थे, राज्य की राजनीति मृत थी। राजनीति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। एक आदमी के इर्द-गिर्द राजनीति घूम रही थी जो मारा तो नहीं गया था, लेकिन लाश बना दिया गया था, जो लोग उसे उसी रूप में स्वीकार किये हुए थे और उसके खिलाफ मुंह खोलना उचित नहीं समझते थे। एमजीआर सार्वजनिक जीवन के पर्याय थे और राज्य मूर्छावस्था में था। इस समय जो कुछ दिखायी दे रहा है, वह मूर्छा से होश में आने की स्थिति है।"

रुग्ण मानसिकता : अपनी निजी जिंदगी में किसी के भी प्रति एमजीआर ने कभी कोई वफादारी नहीं बरती, पर दूसरों से वह पूर्ण वफादारी की सदैव अपेक्षा करते थे। कहा जाता है कि जयललिता के घर उन्होंने नौकर-चाकरों के रूप में जासूस तैनात कर रखे थे। उनके गुप्तचर अधिकारी जयललिता की गतिविधियों और उनके यहां आने-जाने वालों की चौबीसों घंटे निगरानी रखते थे और खबर एमजीआर तक पहुंचाते थे। कहा जाता है कि एक बार वह जयललिता के घर में जबरन घुस गये और वहां मौजूद प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जयशंकर के सीने पर पिस्तौल तान दी। उनको शक था कि दोनों के बीच प्रेम पल रहा है। हालांकि बाद में जयललिता को निपट अकेला छोड़ खुद एमजीआर औरों के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे। सातवें दशक में एक बार जब जयललिता ने अभिनेता सोबन बाबू के साथ विवाह कर गृहस्थी बसाने का प्रयास किया, तो

एमजीआर की विरासत

एमजीआर ने तमिलनाडु की राजनीति को स्थिरता प्रदान की थी, मगर दो गुटों के बीच जारी विरासत की लड़ाई जब निर्णायक दौर में पहुंचेगी, तो यह भी छिन्न-भिन्न हो जायेगी। हां, इस लड़ाई से एक बात यह अच्छी हुई कि एमजीआर की संपत्ति संबंधी ब्यौरा जनता के सामने आ गया। एमजीआर के इस विरासतनामे में कोई सनसनीखेज बात नहीं है और उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा भी अपने सगे-संबंधियों के बीच ही किया है।

एमजीआर ने यह वसीयतनामा १८ जनवरी, १९८७ को पंजीकृत कराया था और यह २८ अप्रैल, १९८६ को तैयार कराये गये वसीयतनामे के स्थान पर था। वसीयतनामे में उनकी चार अचल संपत्तियों के संबंध में जिक्र है। रामवरम स्थित एमजीआर गार्डेन की ६.३४ एकड़ जमीन के बाहर २.२५ एकड़ की खाली जमीन पर मूक एवं बधिर केंद्र बनाया जायेगा। इस केंद्र में खाना, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा की मुफ्त व्यवस्था होगी।

सालिगरामम में ८.३२ एकड़ जमीन पर स्थित सत्य गार्डेन में एक ट्रस्ट बनाया जायेगा, जिसकी कमाई से केंद्र का खर्च चलेगा।

एमजीआर के २७, अर्काट मुदाली स्ट्रीट पर स्थित निवास को 'एमजीआर स्मृति भवन' में तब्दील कर दिया जायेगा। यह निवास जानकी के नाम है, क्योंकि एमजीआर ने बकाया आयकर को चुकाने के लिए इसे उन्हें बेच दिया था। उनका इरादा बाद में इसे खरीद लेने का था। स्मृति भवन में रामवरम और अर्काट मुदाली स्ट्रीट से उपहार सामग्रिया और पुस्तकें लाकर आम जनता के लिए रखी जायेंगी।

अन्य अचल संपत्ति की कमाई, जिसमें मद्रास उपनगरीय क्षेत्र आलंदुर में स्थित पांच मार्केट भवन हैं, रखरखाव में खर्च की जायेगी। अचंल संपत्ति में सत्य स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में एमजीआर के ९५ प्रतिशत शेयर हैं। बाकी के ५ प्रतिशत शेयर जानकी के नाम हैं।

रामवरम और स्मृति भवन के बाकी हिस्से को बेचा नहीं जा सकेगा। साथ ही न तो इसे गिरवी रखा जा सकेगा और न ही दान किया जा सकेगा। सत्य स्टूडियो में एमजीआर के हिस्से की जमीन अन्नाद्रमुक के नाम है, लेकिन पार्टी के टूटने पर मूक-बधिर केंद्र के लिए उसे वापस ले लिया जायेगा। इसके अलावा जो फुटकर संपत्ति है उसका जिक्र वसीयतनामे में नहीं है। कानूनी सलाहकार एन०सी० राघवचारी के अनुसार यह संपत्ति एमजीआर की पत्नी के हिस्से में जायेगी। एमजीआर के लेखा परीक्षक एस० परमशिवराम के अनुसार फुटकर और ऐसी संपत्ति जिसका जिक्र वसीयतनामे में नहीं है, दस करोड़ रुपए के आसपास की होगी।

आश्चर्यजनक खबरें: बहरहाल, कुछ और आश्चर्यजनक खबरें एमजीआर की संपत्ति के बारे में सुनने को मिल रही हैं। कहा जाता है कि कोलंबो में उनका एक पांच सितारा होटल है और श्रीलंका का दौरा करने वाले पत्रकार अकसर वही रुकते थे। सिंगापुर शहर (सिंगापुर) के मध्य में स्थित 'महाराजा शापिंग कांप्लेक्स' में भी एमजीआर के शेयर हैं। १० साल पहले इन शेयरों की कीमत १०० करोड़ थी। अब इन शेयरों की कीमतों में कई गुनी बढ़ोतरी हो गयी होगी। पूर्व फिल्म अभिनेत्री लता उनके इन शेयरों की देखभाल करती थीं। वह वहां एक कैबरे क्लब चलाती हैं। फिल्म कैरियर की समाप्ति के बाद एमजीआर और लता के संबंध भी काफी चर्चित रहे।

यह भी कहा जाता है कि स्विस बैंक सहित कई विदेशी बैंकों में एमजीआर के खाते थे। उनकी संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा इन बैंकों में जमा है। एमजीआर द्वारा किसी को कानूनी वारिस बनाये जाने पर ही यह संपत्ति प्राप्ति की जा सकती थी। इसके अलावा अन्नाद्रमुक सूत्रों के अनुसार एमजीआर ने अपने विश्वसनीय मित्रों, जैसे—शराब व्यापारी रामास्वामी उदय और आर०एम० वीरप्पन के पास भी एक बड़ी रकम जमा करा रखी थी।

पिछली जुलाई में जब एमजीआर बीमार हुए थे, तो उनकी सेहत के बारे में कई अफवाहें उड़ी थीं। जब बाद में एमजीआर अमरीका गये, तो राज्य सरकार में इस बात को लेकर भ्रम बना हुआ था कि वह स्वास्थ्य परीक्षा के लिए गये हैं या इलाज के लिए। वास्तव में एमजीआर की किडनी दूसरी बार खराब हो रही थी और यकृत तो पूरी तरह से खराब हो गया था। डाक्टरों ने दोबारा बड़ा आपरेशन करने से इनकार कर दिया था और वह कोई नया संकट मोल नहीं लेना चाहते थे। वे जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस भेजना चाहते थे। अमरीकी दूतावास के सूत्रों के अनुसार न्यूयार्क में डाक्टरों ने एमजीआर को बता दिया था कि वह २५ से ३१ दिसंबर तक ही जी सकेंगे जबकि डा० फ्रीडमेन जरा ज्यादा आशावादी थे। उन्होंने भारतीय दूतावास को खबर दी थी कि एमजीआर तीन महीने तक जी सकते हैं। एमजीआर जानते थे कि अब वह ज़्यादा दिन नहीं जियेंगे, और अपनी मृत्यु की पूर्व रात में उन्होंने पहले वसीयतनामे (जो कि जनवरी में लिखा गया था और जिसके अनुसार संपत्ति की मालिक जानकी रामचंद्रन थीं) को बदलने की कोशिश की थी। एमजीआर यह भी महसूस करते थे कि वह अपने कार्यकाल का

तीसरा साल भी मुश्किल से पूरा कर पायेंगे (२४ दिसंबर को उनके तीन साल पूरे हुए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गयी)। कहा जाता है कि २३ की रात उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों को बुलाने का फैसला किया और २२ लाख रुपए के स्टांप पेपर खरीदने के आदेश दिये थे। एमजीआर के आलोचकों के अनुसार इस मुद्दे को लेकर एमजीआर और उनकी पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ और इससे उत्पन्न थकान के कारण रात ६ बजे एमजीआर बेहोश हो गये। सूत्रों के अनुसार इसके बाद ४० करोड़ की नगद राशि और २० करोड़ के जेवर आदि रामवरम से 'सुरक्षित' स्थान में पहुंचा दिये गये।

मृत्यु की घोषणा : तीन घंटों के बाद एमजीआर की परीक्षा की गयी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु की खबर सबसे पहले राजीव गांधी को दी गयी और इसके बाद वीरप्पन को। वीरप्पन ने अपने मंत्रियों व कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और झंडों तथा कारों आदि का बंदोबस्त किया। इस व्यवस्था में उन शरारती तत्वों को पैसा देना भी शामिल है, जिन्होंने एम० करुणानिधि की मूर्ति तोड़ी या गंदी की।

जयललिता तड़के ही रामवरम पहुंची, पर उन्हें पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अंदर नहीं घुसने दिया। कहा जाता है कि जयललिता ने एमजीआर से अपनी शादी का प्रमाण-पत्र राज्यपाल एस०एल० खुराना को दिखाया था, तो राज्यपाल ने उनसे संयम बरतने को कहा। जयललिता ने दोबारा रामवरम में प्रमाण-पत्र दिखाने की कोशिश की, मगर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी। घर के सामने ही उन्होंने धरना दिया, मगर एमजीआर का शव गुप्त द्वार से निकाल लिया गया। बाद में जयललिता किसी तरह से कार के पास पहुंच गयीं और शव के नजदीक जगह बनाने में कामयाब हो गयीं। पूरी रात वह शव के करीब बैठी रहीं और उन्हें वहां से हटाने के लिए मारने-पीटने तक की कोशिशें की गयीं। जानकी रामवरम में एक दिन और रहीं। कहा जाता है इसकी वजह अन्य कीमती चीजें घर से दूसरी जगह पहुंचाना था।

एमजीआर ने जयललिता को गोवा-कुल्लू में कुछ फलों के बगीचे और केप कमोरिन में कुछ संपत्ति भेंट की थी। इसके अलावा १ से २ लाख रुपए नगद उन्हें निश्चित समय में मिलते थे।

एमजीआर के पास प्रचुर मात्रा में धन था और अपने चहेतों को वह खुलकर बांटते भी थे, लेकिन इसके पीछे स्वार्थ जरूर होता था।

—विजय दत्त और उषा सुंदरम

एमजीआर मार्ग में रोड़ा बन गये। वैसे लोगों का कहना है कि सोबन बाबू ने जयललिता से मित्रता तो जरूर की थी, किंतु वह अपनी पत्नी को छोड़कर जयललिता से विवाह करने के पक्ष में नहीं थे। जयललिता के पूर्व मित्रों के अनुसार सोबन बाबू ने एक बार शादी का वायदा कर पुरोहित लाने की बात तक की थी, पर वह पलट कर नहीं आये। उस समय एमजीआर पुनः जयललिता की जिंदगी में आये और अंततः उन्हें पार्टी (अन्नाद्रमुक) में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया।

मुहब्बत और नफरत के इस खेल ने महज दोनों की ही निजी जिंदगी को प्रभावित नहीं किया, बल्कि तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम को भी अछूता नहीं छोड़ा। एमजीआर जब-जब जयललिता से प्रसन्न होते, तब-तब वह अपार शक्ति संपन्न होती थीं। किंतु जयललिता की वफादारी पर थोड़ा भी संदेह होते ही, उन्हें दूध की मक्खी की तरह वह निकाल फेंकते थे। और ऐसा अकसर होता था। जयललिता के टेलीफोन तक 'टेप' होते थे और खुशामदी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास उसे नियमि रूप से पहुंचाते थे। जयललिता के राज्यसभा सदस बनने के बाद भी उन पर सख्त निगरानी का यह क्र कभी नहीं टूटा।

इससे आजिज आकर जयललिता ने १९७ ७८ के दौरान विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इ दौरान उन्होंने ६०० लंबे पृष्ठों में अपने औ एमजीआर के संबंधों का कच्चाचिट्ठा कलमबं किया। उनकी एक बालसखा के अनुसार, "मैं त भारी भरकम संस्मरण-पुलंदे का आधा भाग भ नहीं पढ़ सकी। किंतु मैंने उसको (जयललिता को यह सलाह जरूर दी कि वह उसे प्रकाशित कराये।" हुआ भी ऐसा ही लेकिन अविश्वा जारी रहा।

चो रामास्वामी के कथनानुसार एक बा जयललिता ने फोन करके उनसे पूछा कि एमजीआ भरोसे लायक हैं या नहीं? यह उनके अन्नाद्रमुक शामिल होने के समय की बात है। चो ने जवा दिया, "अम्मू' (जयललिता को पुकारने का नाम

[illegible] छवि : एमजीआर एक वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए

फ़ोन एमजीआर को दे दो।" जयललिता ने तुरंत फ़ोन काट दिया। चो का खयाल है कि एमजीआर, (जिन्हें इस तरह के ख़ेल में विशेष आनंद आता था) ने खुद जयललिता के बगल में बैठकर यह फोन करवाया था।

कृतज्ञता किस चिड़िया का नाम है इसका इल्म एमजीआर को नहीं था। १९८४ में एमजीआर जब मरणासन्न थे, तो उनके भाई चक्रपाणि की पुत्री ने अपना गुर्दा दान करके एमजीआर की जीवन रक्षा की थी। किंतु वसीयत लिखते समय उनको अपनी भतीजी का नाम तक याद नहीं रहा। जानकी के पहले पति गणपति भट्ट की चार वर्ष पूर्व ही मृत्यु हुई थी और मरने से पहले वह पाई-पाई को मोहताज थे। वैसे एमजीआर की इस मामले में कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, किंतु वह उनकी पत्नी जानकी को उड़ा कर लाये थे, इस नाते दयनीय अवस्था में उनकी कुछ सहायता तो करनी ही चाहिए थी।

जानकी की हैसियत : जानकी उनकी कानूनी धर्मपत्नी हैं, इस पर भी संदेह किया जा रहा है। आम धारणा है कि उनका एमजीआर से उस समय विवाह हुआ था, जब एमजीआर की पहली पत्नी क्षय रोग से ग्रस्त थीं और उसका अंत निकट था। किंतु उनकी आशा के विपरीत पहली पत्नी काफी अरसे तक जिंदा रही। यही हाल भट्ट का भी था। अतः प्रश्न उठता है कि शादी हुई भी, तो कब, कैसे और किस स्थिति में?

कुछ वर्ष पूर्व अफवाह फैली थी कि एमजीआर-जानकी की शादी से संबंधित एक पुरोहित का शपथपत्र और न्यायाधीश की अदालत का रजिस्ट्रीशुदा मसौदा वीरप्पन के पास है। इससे यह सिद्ध होता था कि एमजीआर ने यह पुनर्विवाह अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद किया था। किंतु इसमें उल्लिखित तिथि ने इस बात को गलत साबित किया, क्योंकि उस तारीख तक उनकी पूर्व पत्नी मरी नहीं जीवित थी। इसी बीच जोर-शोर से खबर फैली कि जयललिता की मंगलौर के कोलर जिले में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सरस्वती पीठ के मोकम्बिका मंदिर में एमजीआर से विवाह हो गया है।

एमजीआर ने इन अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने इनको फैलाने में मदद कर दोनों महिलाओं की मुसीबत सांसत बढ़ायी। परपीडा और प्रतिशोध सीमातीत होता है। किंतु अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पार्टी के महारथियों को इन दोनों महिलाओं को उभारने और अपने अहं और आत्मसम्मान को ताक पर रखने के अलावा और कोई चारा नहीं। पेरियार के चेले और अन्नादुरै के. सहायक ६७ वर्षीय नेदुनचेझियन का सारा रुतबा जब एमजीआर ने छीन लिया था, तो उन्हें जयललिता का पल्लू पकड़ना पड़ा था। इसी प्रकार एस०डी० सोमासुंदररम, जिन्होंने एमजीआर द्वारा जयललिता को प्रमुखता दिये जाने से पार्टी छोड़ दी थी, अब उनके (जयललिता) आशीर्वाद के मूक आकांक्षी हैं। इसी तरह जयललिता को भी, भले ही

सत्ता और रुमानियत का साथ : एक फिल्म में एमजीआर और जयललिता

एक फिल्म में एमजीआर और मंजुला।

वह एमजीआर की पत्नी रही हों या प्रेमि
दिवंगत नेता के लाखों शोकग्रस्त समर्थकों के सम्
जानकी-भाई-भतीजों की धक्कामुक्की सहनी प

अविश्वासों, प्रतिशोधों, संदेहों, ताड़नाओं
सुदीर्घ घात-प्रतिघातों का फल आज तमिलनाडु
मिल रहा है। किंतु विडंबना यह है कि
खमियाजा उस जनता को भुगतना पड़ रहा है
सम्मोहक व्यक्तित्व वाले एक ऐसे व्यक्ति के हाथ
कठपुतली बन गयी थी, जिसने सहृदयता का
मुखौटा लगा रखा था, लेकिन जो दरअसल
दिल और बदले की भावना से ग्रस्त था। इसके च
उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा, जिसमें फंस कर उ
बाद उत्तराधिकारी बनने की कामना रखने वा
को हिंसा और अपमान का सामना करना पड़े

तमिलों के सबसे बडे त्यौहार पोंगल की
संध्या पर जयललिता और नेदुनचेझियन स
पांच पूर्व मंत्रियों को धकिया कर पुलिस जीप में
दिया गया। जयललिता के माथे पर लाठी लगी अ
उनको बचाने के प्रयास में उनके सुरक्षाकर्मी
खोपड़ी फट गयी। परपीड़ा की इस थाती
विडंबना यह है कि जयललिता ने जहां अपने बं
की बालकनी के नीचे एकत्र विशाल भीड़ से
हिंसक घटना का वर्णन किया, वहां दरवाजे के बा
एमजीआर के चित्र और पोस्टर बिक रहे थे अ
नर-नारी जयललिता की व्यथा सुनने के ब
पटरियों पर बिक रहे अपने प्रिय नेता के चित्रों
खरीदने में लगे थे। तमिलों ने वर्षों तक अपने
नायक को अपार स्नेह और धन दिया है, जिसके ब
में अनेक की राय है कि उसने केवल स्त्रियों को
नहीं, उन पुरुषों के साथ भी न्याय नहीं किया
उनकी पूजा करते थे।

ऐसा नहीं लगता कि जानकी का शासन
इस 'परंपरा' से कोई भिन्न सिद्ध होगा। यह ब
दूसरी है कि वह चलता कब तक है। सवाल च
और न चलने का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि द्रवि
पार्टियों का यह तमाशा तमिलनाडु को कहां
जायेगा ? इस व्यक्तिपूजा और उठापटक के का
तमिलनाडु ने बहुत कुछ खोया है। यहां के लो
अतीत की ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन
समय की स्थितियों से यह भी आभासित होता है
उनको अपने भविष्य की भी उतनी चिंता नहीं।
स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह
उनसे लूटी गयी संपदा का राजनीति में भों
प्रदर्शन हो रहा है। कुछ भी हो, एमजीआर ने दो
महिलाओं को और कुछ दिया हो या न दिया ह
लेकिन दोनों को 'उनके' एमजीआर ने आपस
लड़ने के लिए पूर्ण दीक्षित कर दिया है।

जानकी इस रूमानी याद से ही संतुष्ट हों
कि उनकी अधेड़ावस्था में एमजीआर ने उन
'अपहरण' किया था और जयललिता की स्मृति में
दृश्य कौंध रहे होंगे, जब शूटिंग के दौरान तपती रे
पर उनके पांवों की जलन को देख कर एमजीआ
कंधों पर उठा लिया करते थे और तमिलनाडु
सत्ता और रूमानियत का हमेशा साथ रहा है।

■

हरिजन किधर जायेंगे ?

अभी तक कांग्रेस हरिजनों को अपना 'वोट बैंक' समझती रही है। यही नहीं पं० नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कुछ हरिजन नेताओं को हरिजनों का महंत तक बनाकर भी रखा और उनसे फ़ायदा भी उठाया, लेकिन इधर कांग्रेस ही नहीं विपक्षी राजनीति से भी हरिजन नेताओं का मोहभंग हो रहा है तथा उनके स्वयं के नेता और संगठन उभड़कर सामने आ रहे हैं। क्या अब हरिजन राजीव गांधी से दूर हो जायेंगे ?

२१ वीं शताब्दी में बेहतर जिंदगी की प्रतीक्षा

हरिजन राजीव गांधी के साथ बने रहेंगे या तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ वे भी कोई नया रुख अख्तियार करेंगे? देश की कुल आबादी का यह चौदह प्रतिशत हिस्सा आखिर किसका साथ देगा? ये सवाल भले ही अभी गरम बहस के विषय नहीं हैं, पर अंदरूनी रूप से हर राजनीतिक दल को ये सवाल मथ रहे हैं। वैसे अधिकांश विपक्षी दलित नेता बेहद बेचारगी से यह स्वीकारते हैं कि हरिजन कांग्रेस के पास बंधक पड़े हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि वे इतना अधिक टूटे हुए हैं कि सत्ता से दूर रहने पर उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति पर भी खतरा नजर आता है। इसलिए सुरक्षा पाने के लिए हरिजन के पास कांग्रेस की उगली थामे रहने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पर क्या अपने नाना और अपनी मां की तरह राजीव गांधी अपने इस पारंपरिक वोट बैंक पर कब्जा बनाये रख सकेंगे? डा० बाबासाहब अंबेडकर की धर्मपत्नी डा० सविता अंबेडकर कहती हैं, "राजींव को पता ही नहीं कि यह हरिजन क्या बला हैं?" क्या हरिजन उस 'जनमोर्चा' की तरफ भी मुखातिब हो सकते हैं जिसके संयोजक हरिजन नेता रामधन हैं? और क्या १६७७ के चुनावी नतीजों को स्मरण कर ही वी०पी० सिंह ने रामधन को मोर्चे का संयोजक बनाया है? १६७७ में जनता पार्टी को अनुसूचित जाति के शत-प्रतिशत मत मिले थे और काफी तादाद में हरिजन सांसद जीते थे। तब ऐसा लगा था कि माहौल बदलने पर सहमा हुआ हरिजन मतदाता भी कांग्रेस से पल्लू झाड़ने का साहस दिखा सकता है। जनता पार्टी की जीत के बाद स्व० जयप्रकाश नारायण जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इससे एक आदर्श भी स्थापित करने की नीयत थी कि जनता पार्टी ने एक हरिजन नेता को प्रधानमंत्री बनाकर प्रगतिशीलता का परिचय दिया है। पर जे०पी० को कामयाबी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि जगजीवन राम का व्यक्तित्व कभी प्रगतिशील नहीं रहा। हरिजन नेता के रूप में वह मुहरबंद भी नहीं होना चाहते थे, जबकि सत्ता से बाहर रहकर उन दिनों भी श्रीमती गांधी हरिजन-प्रेमी छवि के प्रति सतर्क थीं। इसलिए बिहार के बेलछी में जब चौदह हरिजनों को जिंदा जला दिया गया, तो फौरन श्रीमती गांधी दलबल सहित वहां पहुंच गयीं। बेलछी यात्रा से श्रीमती गांधी को गर्दिश के दिनों में भी अखबारों की सुर्खियां मिल सकीं। बहरहाल, जनता सरकार के गिरने के बाद हुए चुनाव में हरिजन मतदाता फिर वापस कांग्रेस में लौट आया। इससे जाहिर हुआ कि जब तक कोई असाधारण लहर नहीं हो, हरिजन मतदाता विचलित नहीं होता। लहर में बहकर यदि वह कहीं दूसरे ठिकाने पर पहुंच भी गया, तो फिर से खरामा-खरामा कांग्रेस में लौट जायेगा।

निष्फल प्रयास : आजादी के बाद दलितों के मसीहा डा० बाबासाहब अंबेडकर ने 'शिड्यूल कास्ट फेडरेशन' की ओर से दलित नेतृत्व को एक अलग अस्तित्व देने की पहल की थी, पर वह प्रयास बुरी तरह विफल रहा और इतना ही नहीं बाबा साहब खुद भी चुनाव हार गये। इसके कई दशक बाद जब जगजीवन राम को नेता बनाकर जनता पार्टी लड़ी, तो भी वैसी ही निराशा हाथ लगी। बिहार के भूतपूर्व हरिजन मुख्यमंत्री रामसुंदर दास इसका सुंदर विश्लेषण करते हैं, "हरिजन नेतृत्व जैसा कुछ अलग से हो ही नहीं सकता। इसका कारण है कि आज तक कोई भी हरिजन नेता प्रभावशाली साबित नहीं हो सका। इसलिए विपक्षी मोर्चे से भी जब कभी किसी हरिजन नेता को अगुआ बनाकर राजनीति करने की कोशिश की गयी, तो विफलता ही मिली। अभी रामधन 'जनमोर्चा' के संयोजक हैं, पर उनका अस्तित्व मोर्चे में दोयम दर्जे पर है, यह सभी जानते हैं। इसलिए किसी दलित नेता को जब भी पहले नंबर पर लाया गया है, तो यह बात स्पष्ट रूप से झलकती रही है कि जो हैसियत उसे दी गयी है, सही मायने में दल में उसकी वह हैसियत है ही नहीं। लिहाजा, आम हरिजन मतदाता सत्ता का बंधुआ मजदूर बने रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसमें उसे कहीं से 'रिस्क' नहीं दिखती है। हां, इतना जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भले न सही, पर देश के सुदूर इलाकों में छोटे-छोटे दायरे में दलितों के कई विस्मयकारी नेतृत्व उभर रहे हैं। अगर ऐसे नेतृत्व अरसे तक कायम न भी रहें, तो भी जो छाप वह छोड़ जायेंगे, उसका प्रभाव काफी समय तक बना रहेगा।"

केवल शो पीस : ऐसी बात नहीं है कि अपने नाना और अपनी मां से विरासत में हासिल हरिजन मतदाताओं को बटोरे रखने में राजीव गांधी उदासीन हैं। अपने पिछले चुनाव में उन्हें किसी भी जाति या वर्ग का कोई समीकरण बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। पर बाद के दिनों में राजींव इसके लिए काफी सजग हुए और यह भी एक वजह थी कि जगजीवन राम को उनके आखिरी दिनों में काफी तरजीह दी गयी थी। साथ ही उन्हीं के जीवनकाल में उनकी पुत्री मीरा कुमार को भी संसद में ले जाया गया। पर इसके बावजूद दलित नेतृत्व की कमान कांग्रेस में किसे सौंपी जाये, इसके लिए राजीव गांधी काफी गंभीर थे। जैसा कि श्रीमती गांधी ने अरसे तक कांग्रेस में जगजीवन राम को दलित राजनीति के महंत के रूप में प्रतिष्ठित रखा था, ठीक उसी तरह राजीव भी कांग्रेस के लिए एक हरिजन महंत की टोह में थे जो कांग्रेस में हरिजन मतदाता को टिकाये रख सकने का माध्यम बनता। इसी क्रम में इंका में उपेक्षित पड़े सांसद रामधन पर

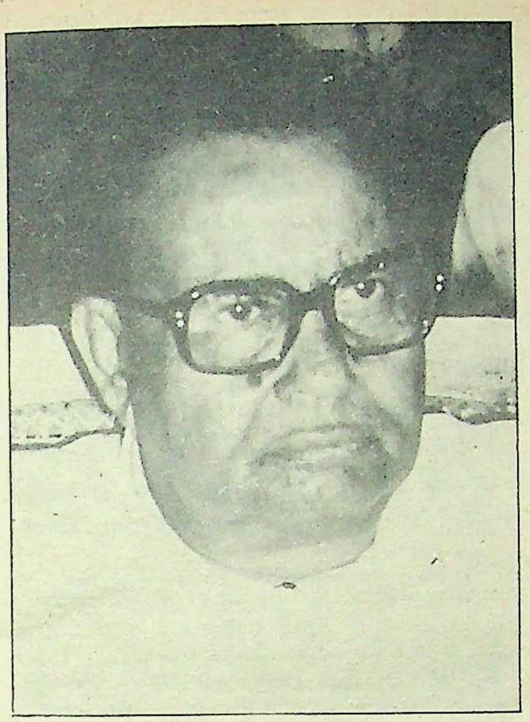

केवल शोभा के लिए: डुमरलाल बैठा

राजीव की दृष्टि गयी जो उनकी मां के समय से गर्दिश में रहे थे। बस तय हो गया कि इस बौद्धिक हरिजन नेता को दलित-राजनीति का तुरुप बनाया जाये। रामधन आनन-फानन में इंका के महासचिव बना दिये गये। पर राजीव के इस अनुग्रह से रामधन शायद इस गलतफहमी के शिकार हो गये कि जैसे श्रीमती गाधी की हुकूमत में बाबूजी का हरिजन-महंत होने के नाते सम्मान था, उसी हैसियत से राजीव ने भी उन्हें दलित-राजनीति में 'प्रोजेक्ट' किया है। और यहीं रामधन से चूक हो गयी। दरअसल, राजीव को रामधन से एक ऐसे हरिजन नेता की भूमिका की अपेक्षा थी जो उनसे कतई सम्मान की हसरत न रखकर बस दलितों को लुभाने का 'शो पीस' बना रहे। रामधन राजीव की इस अपेक्षा को समझ नहीं सके, क्योंकि वी०पी० सिंह के साथ जैसी भूमिका आज वह प्रसन्नतापूर्वक निभा रहे हैं, लगभग वही भूमिका उन्हें राजीव के संग भी निभानी थी। इसलिए चाहे राजीव गांधी हों या वी०पी० सिह, हरिजन-नेतृत्व के लिए दोनों की समझ एक सी है। उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। दोनों को ऐसे हरिजन-नेता की दरकार है जिसकी न कोई ताकत हो न कोई राय। फर्क यही है कि कांग्रेस में रहकर जो रामधन हरिजनों के चुंबक हो सकते थे, वही जनमोर्चा के संयोजक होने के बावजूद हरिजन मत बटोर पाने में शायद ही कामयाब हो पायें। कड़वा सच यही है कि विपक्ष की राजनीति करनेवाला हरिजन नेता बस खुद एक अपनी सीट जीत ले जाये, वही उसके लिए बड़ी बात होती है। पर कांग्रेस में जाकर वही हरिजन नेता हरिजनों का 'वोट-कैचर' और रहनुमा बन जाता है।

यही वजह है कि एक जमाने में बी०पी० मौर्य की कांग्रेस में रहकर जो हैसियत थी, आज वह लोकदल में रहकर नहीं है। मुखर हरिजन युवा तुर्क रामबिलास पासवान शुरू से ही विपक्ष की राजनीति में रहे, पर आम चुनाव में हारने के बाद उपचुनाव लड़ने पर भी वह संसद में अपने लिए एक सीट हासिल नहीं कर सके।

बहरहाल, रामधन की बग़ावत के बाद राजीव गांधी को एक ऐसे हरिजन नेता की तलाश थी जो रामधन जैसा तेज मिजाज न हो।आखिरकार बिहार के हाजीपुर से सांसद रामरतन राम सामने आये, जिनका बिहार की राजनीति में भी कोई स्थान नहीं था। रामरतन महासचिव पद पा गये। स्पष्ट है कि देश की राजनीति में दलित नेतृत्व के नाम पर वह युग गया जब स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी उठकर बाबूजी को सम्मान देती थीं। अब यह रामधन और रामरतन राम का युग है। सत्ता में जुड़ा दलित नेतृत्व भी अपनी बौनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ है। पर यह बौनी हैसियत वाला तबका ऊंची मीनार पर खड़ा है जबकि विपक्ष के दलित नेता जानते हैं कि चाहे वे कितनी भी वरजिश कर लें, उस मीनार तक नहीं पहुंच सकते।

उत्तर भारत में राजीव दलितों के प्रति खासे चौकन्ने हैं। इसलिए उत्तर भारत के दो प्रांतों उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हरिजन हैं। उत्तर प्रदेश में महावीर प्रसाद और बिहार में डुमरलाल बैठा। बेशक इन दो अधिक संसदीय सीटों वाले प्रांत में कांग्रेस संगठन की बागडोर हरिजन नेताओं के हाथ में है, लेकिन इनकी हैसियत कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां महावीर प्रसाद मिट्टी के माधो साबित हुए हैं, वहीं बिहार में इंका अध्यक्ष डुमरलाल बैठा को मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है।

अब अमुख्य: पूर्वमुख्यमंत्री रामसुंदर

संघर्ष की तैयारी: करमाराम सुंडा

नये कांशीराम? : मैकूराम

अन्य विपक्षी दलों मसलन, लोकदल, जनता पार्टी, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी आदि में दलित नेता दिखावे के लिए भी महत्व की स्थिति में नहीं हैं। लोकदल-ब से हताश होकर रामबिलास पासवान जनता पार्टी में आ गये हैं। हरिजनों के बीच उनका अच्छा आधार भी है, पर जनता पार्टी में वह 'अतिसामान्य' बने हुए हैं। सवाल यह है कि राजनीतिक दलों में हाशिया पर छितराया हुआ हरिजन-नेतृत्व कहां ठौर पायेगा और क्या कभी राजनीतिक हाशिए से अपनी अस्मिता के बचाव के लिए निकल भी पायेगा। महाराष्ट्र के युवा दलित नेता गंगाधर गाड़े कहते हैं, "कुछ नहीं होगा जब तक हरिजन नौजवान गांव-गांव में किसी राजनीतिक दल का मुंह जोहे बगैर ईंट-से-ईंट नहीं बजा देंगे।"

बहुजन समाज पार्टी: 'बहुजन समाज पार्टी' और उसके नेता कांशीराम क्या दलितों को राष्ट्रीय नेतृत्व का धरातल सुलभ करा पायेंगे? यह सवाल देश के दलित नेताओं के मन में उठता रहा है। इंका से लेकर विपक्ष के दलित नेताओं की राय में निस्संदेह बहुजन समाज पार्टी अचानक एक नयी शक्ति के रूप में उभरी है, पर कोई सार्थक फलाफल हरिजन नेतृत्व को पैना बनाने में नहीं दे पायी है। उलटे इससे विपक्ष के हरिजन नेताओं को ज्यादा नुकसान ही हुआ है। मिसाल के लिए बिजनौर के उपचुनाव में विपक्षी प्रत्याशी रामबिलास पासवान की पराजय का कारण बहुजन समाज पार्टी ही बनी, क्योंकि इसके प्रत्याशी ने जो साठ हजार से अधिक मत पाये, वह रामबिलास के खाते से ही गये, अन्यथा इस उपचुनाव में रामबिलास जगजीवन राम की बेटी को मात दे देते।

दूसरे, हरिजन नेतृत्व के साथ जो एक सबसे गहरा संकट है, वह यह कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई ऐसा हरिजन नेता नहीं जिसका नेतृत्व हरिजनों के बीच में एकमत से स्थापित हो। रामधन हरिजन नेता हैं भी, तो अधिक-से-अधिक केवल उत्तर प्रदेश के। रामबिलास पासवान भी बस कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र तक ही सिमटे हुए हैं। डा० अंबेडकर की धर्मपत्नी सविता अंबेडकर द्वारा संचालित संगठन 'दलित पैंथर' का भी असर महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। दक्षिण भारत के हरिजनों पर इन नेताओं का लेशमात्र प्रभाव नहीं है। केरल के राजन यों कैथोलिक ईसाई हैं, पर दलितों की राजनीति से गहरे जुड़े हैं और 'दलित सेना' की युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं। राजन कहते हैं, "केरल में दलितों के कई सार्थक आंदोलन चले और अब वहां के हरिजन उत्तर प्रदेश और बिहार के हरिजनों से बहुत बेहतर हालत में हैं। केरल के हरिजनों में शिक्षा भी काफी है। यों केरल की २० संसदीय सीटों में सिर्फ दो ही अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं जिनमें ओट्टालम से के०आर० नारायण और अडूर क्षेत्र से के० कुंजाबू इंका सांसद हैं। केरल के दलित उत्तर भारत के दलितों की तरह आं

साक्षात्कार/डा० सविता अंबेडकर

'दलित क्या हैं, राजीव नहीं जानते'

बंबई के पश्चिमी दादर क्षेत्र में स्थित 'मातरुछाया' में अपने भाई डा० कबीर के साथ रहती हैं दलितों के ऐतिहासिक पुरुष डा० बाबासाहब अंबेडकर की ७२ वर्षीया धर्मपत्नी डा० सविता अंबेडकर। अपने पति के इन आखिरी शब्दों को कि 'अगर आप इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते, तो कम-से-कम इसे पीछे भी मत जाने देना' उम्र के इस पड़ाव पर भी निभाने के लिए सविता अंबेडकर जुटी हुई हैं। 'दलित पैंथर' नामक संगठन की प्रधान सविता अंबेडकर वाकई एक अनोखी शख्सीयत हैं। एक सुसंस्कृत मराठी ब्राह्मण परिवार की सविता उन दिनों बंबई के 'ग्रैंड मेडिकल कालेज' की छात्रा थीं जब वह बाबासाहब के सान्निध्य में आयीं थीं और बाद में उनकी जीवनसंगिनी भी बन गयीं। दलितों के हक की बहाली के लिए सविता अंबेडकर की मुहिम खत्म नहीं हुई है। देश की मौजूदा दलित राजनीति के बाद डा० सविता अंबेडकर से 'माया' ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं, उसी बातचीत के प्रमुख अंश:

माया: आजादी के पहले और आज के दलित नेतृत्व में आप क्या अंतर पाती हैं?

सविता: सही मायने में डा० बाबासाहब अंबेडकर के बाद दलितों के बीच से कोई कारगर नेतृत्व उभरा ही नहीं और यही सबसे बड़ी विडंबना है। डा० अंबेडकर की विचारधारा पर इसीलिए अमल नहीं हो सका। अपने मुल्क में दलित नेतृत्व को हरदम दबाये रखने की साजिश होती रही है। डा० अंबेडकर को भी कुचलने के लिए उस समय के दिग्गज नेताओं ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। दलित नेतृत्व के कुंद रहने की एक और वजह थी कि बाद के दिनों में जो भी नेतृत्व सुगबुगाया, वह संघर्ष करने को तैयार नहीं था। साथ ही दो नंबर का रोल करना किसी को गवारा नहीं था। सबको मंच पर जगमगाने की ललक थी। गांवों में जाकर एड़ियां रगड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। डा० अंबेडकर के निधन के बाद उनके अनुयायी भी नेतृत्व के लिए लड़ने लगे। 'रिपब्लिकन पार्टी' जिसकी परिकल्पना डा० अंबेडकर ने की थी, उसका जन्म उनके निधन के बाद हुआ, पर अतिमहत्वाकांक्षी दलित नेताओं के कारण सब कुछ बिखर गया।

माया: कांग्रेस और विपक्ष के दलित नेतृत्व में किस तरह का फर्क है?

सविता: इसमें कोई शक नहीं कि दलित-हरिजनों पर कांग्रेस की जागीरदारी रही है, पर कांग्रेस से जुड़ा दलित नेता अपने चरित्र से दलित नहीं रह जाता। हां, वह दलित होने का आधिकारिक सुख जरूर उठाता है। देश के आम दलित को इनसे कभी राहत नहीं मिली। स्व० जगजीवन राम अरसे तक सत्ता-शीर्ष पर रहे। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, यह शायद बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने तो सदैव से दलित वोटों पर कब्जा कर दलितों को मन से तोड़ा है, ताकि कभी वह हक के लिए हंगामा न कर सके। यह मुहिम महात्मा गांधी के समय से ही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि गांधीजी ने दलितों के उत्थान का बस ढोंग किया। वह दिल्ली की हरिजन कालोनी में कभी-कभार रह तो लेते थे, पर हरिजनों के हाथ की पकी रोटियां नहीं खाते थे। डा० अंबेडकर को दोयम दर्जे पर रखने की कम कोशिश उन्होंने नहीं की थीं। 'पूना पैक्ट', जिसमें 'सेप्रेट एलेक्टोरेट' की मांग जोरदार ढंग से डा० अंबेडकर ने उठायी थी, पर गांधीजी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गये थे। आखिरकार गांधीजी का लिहाज करके डा० अंबेडकर ने वह मांग वापस ले ली थी। उन दिनों वानखेड़े, गणेश गवई और थोरें आदि कई नेताओं को बाबासाहब को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेरी समझ में दलित नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने के लिए गांधीजी ने नेपथ्य में जो खतरनाक खेल खेला था, उसी का असर है कि दलित नेतृत्व अभी भी इंकलाबी तेवर में नहीं आ पाया है। आज विपक्ष के दलित नेताओं की तो मामूली हैसियत भी नहीं है। वी०पी० सिंह ने रामधन को 'जनमोर्चा' का संयोजक बना रखा है, पर उस बेचारे की क्या हैसियत हैं उस मोर्चे में। इस 'बेसहारा' की स्थिति से दलित नेतृत्व को उबरना होगा।

माया: चुनाव में कई बार आप भी खड़ी हुईं और आपके पौत्र प्रकाश अंबेडकर भी, लेकिन हरबार निराशा ही हाथ लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दलितों के बीच में बाबासाहब का प्रभाव क्षीण हो गया है?

सविता: चुनाव में तो स्वय डा० अंबेडकर भी कभी नहीं जीत सके थे। लोकसभा के लिए वह दो बार खड़े हुए थे। एक बार भंडारा से और दूसरी बार नार्थ बंबई से। दोनों बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, पर इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि बाबासाहब की लोकप्रियता या सम्मान में कोई कमी थी। डा० अंबेडकर 'शिड्यूल कास्ट फेडरेशन' की ओर से खड़े हुए थे। देश के तमाम नेताओं ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। चुनाव हम भी लड़ते हैं और हारते हैं, पर इससे हताश नहीं हैं हम। जीवन के हर स्तर पर पराजय से उपजी हताशा ने दलितों को तोड़ा है, पलायनवादी बनाया है। हम हार गये, पर खड़े तो हुए। हमारी हाजिरी तो दर्ज हुई। हारने के डर से दलित अगर बैठा ही रह जायेगा, तो कभी उठ नही सकेगा। रायबरेली के चुनाव में जब मैं खड़ी हुई थी, तो दलितों के घर-परिवार की औरतें व अन्य लोग पूछते, "कौन थे यह बाबासाहब अंबेडकर?" मुझे आश्चर्य और दुख भी होता था। अशिक्षा ने दलितों को उन लोगों के नाम तक से अब तक दूर रखा है जो लोग उनके लिए लड़ते रहे।

माया: अभी पिछले दिनों डा० अंबेडकर की किताब 'रिडल्स इन हिंदुइज्म' के कुछ अध्याय को लेकर उठे विवाद के कारण महाराष्ट्र सरकार ने बहुत से अंश पुस्तक से निकाल दिये। आपने सरकार के इस कदम को किस तरह लिया है?

सविता: डा० अंबेडकर की बस अप्रकाशित कृतियों के प्रकाशन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने ले रखी है। तीन खंड तो छप गये। चौथा खंड था 'रिडल्स इन हिंदुइज्म'। इसमें डा० अंबेडकर ने वाल्मीकि रामायण के विवरणों को आधार बनाकर राम व कृष्ण पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने योग्य नहीं थे और न ही कृष्ण में नैतिकता का भाव था। यह एक आलोचनात्मक व्याख्या है जो डा० अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में की है। 'मराठा महासंघ' नामक एक संगठन ने इसी प्रसंग को लेकर बावेला मचाया और उस किताब की प्रतियां

जलायीं। घबड़ाकर महाराष्ट्र सरकार ने उन अंशों को पुस्तक से निकाल दिया। विरोध में हम लोगों ने भी बंबई में लाखों लोगों का जुलूस निकाला। अगर पुस्तक से उस अंश को निकालने पर सरकार अड़ेगी, तो दलित भी बैठे नहीं रहेंगे।

माया : पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी का दलितों के वास्ते क्या रुख था और अब राजीव गांधी का क्या रवैया है?

सविता : पंडित नेहरू सही मायने में दलितों से हमदर्दी रखते थे, पर इंदिराजी का दलितों के लिए दिखावा ज्यादा था, अपनापन कम। वह रूढ़िवादी सनातनी महिला थीं। राजीव गांधी समझते ही नहीं कि यह हरिजन क्या बला है, कौन-सी नस्ल है।

माया : उन प्रांतों में जहां, गैर कांग्रेसी सरकारें हुकूमत में हैं, दलित किस हाल में हैं?

कांग्रेस ने तो सदैव से दलित वोटों पर कब्जा कर दलितों को मन से तोड़ा है, ताकि कभी वह हक के लिए हंगामा न कर सके। यह मुहिम महात्मा गांधी के समय से ही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि गांधीजी ने दलितों के उत्थान का बस ढोंग किया। वह दिल्ली की हरिजन कालोनी में कभी-कभार रह तो लेते थे, पर हरिजनों के हाथ की पकी रोटियां नहीं खाते थे। डा० अंबेडकर को दोयम दर्जे पर रखने की कम कोशिश उन्होंने नहीं की थी।

सविता : कर्नाटक, केरल व पश्चिम बंगाल में दलितों की दशा बहुत अच्छी नहीं, तो बहुत बुरी भी नहीं है, पर आंध्र प्रदेश में दलित ज्यादा बेहाल हैं।

माया : आखिर किस तरह दलित नेतृत्व अपनी लड़ाई की दिशा तय कर सकता है?

सविता : दलित नेतृत्व को अपना दब्बूपन इसके लिए झटकना पड़ेगा। गांवों में तबाही भुगत रहे, बेकसूर मारे जा रहे, अपराधी करार कर जेलों में ठूंसे जा रहे आम दलित-हरिजन की व्यथा जिस पल दलितों की नेतागिरी करनेवालों को सिहरा देगी, उस दिन सारी दिशा खुद तय हो जायेगी।

—विकास कुमार झा

छाया : प्रभाकर

राजनीति में सक्रिय : केरल के राजन

नयी पीढ़ी का नेतृत्व : नागभूषण

केवल नाम के लिए : रामरतन राम

मूंदकर किसी दल को वोट नहीं डालते। वे पहले तौलते हैं कि कौन उनके हक को दिलाने में सक्षम है। इसलिए केरल के विधान-सभाई चुनाव में हरिजनों ने वामपंथियों को वोट दिये।"

जागरण के लक्षण : कर्नाटक में भी दलित काफी कुछ जागृत हुए हैं, पर उत्तर भारत का दलित बहुत चाहकर भी अपने दब्बू नेतृत्व के कारण ऊपर नहीं आ सका है। "दलित नेतृत्व की एक नयी नस्ल तैयार हो रही है," कहना है बिहार पुलिस सेवा में महानिरीक्षक मैकूराम का, जो अभी पिछले दिनों 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ, बिहार' के अध्यक्ष की हैसियत से अपने वक्तव्यों के चलते सुर्खियों में रहे। मैकू कहते हैं कि हम जैसे सरकारी अधिकारी जब अवकाश ग्रहण कर फुर्सत पायेंगे, तो बैठे नहीं रहेंगे और बगैर किसी राजनीतिक दल में गये हरिजनों के उन्नयन के लिए काम करेंगे। मैकूराम पिछले दिनों अपने संघ के मंच से जब अनुसूचित जाति के हक को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ मुखर हुए, तो सरकारी स्तर पर खलबली मच गयी। मैकू कहते हैं कि अब जहां कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में संघ का कार्यक्रम होता है, अनुसूचित जाति के कर्मचारी हजारों की तादाद में उमड़ पड़ते हैं।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मूल बाशिंदे और बिहार में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी मैकूराम क्या कांशीराम बनना चाहते हैं? 'माया' के इस सवाल पर मैकू कहते हैं, "काशीराम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वह राजनीति में हैं और मैं सरकारी सेवा में हूं। भविष्य में भी मैं राजनीति में आने की बात नहीं सोचता।" इसी तरह कई छोटे-छोटे नेतृत्व विभिन्न प्रांतों में सुगबुगा रहे हैं। दिल्ली के करमा राम सुंडा भी इन्हीं में एक हैं। करमा राम १९८४ तक भारत सरकार में संयुक्त निदेशक व सह उपसचिव, रोजगार थे। अवकाश ग्रहण करने के बाद करमा राम ने १४ नवंबर, १९८७ को दलितों का एक संगठन बनाया— 'भारतीय शोषित दल'। करमा राम कहते हैं, "भारतीय समाज में धन, धरती और धंधा कुछ खास वर्ग तक ही सिमटा रह गया। यह असमानता आज भी बरकरार है। 'शोषित दल' इसी के खिलाफ अलख जगायेगा।"

बहरहाल, मैकूराम या करमा राम सुंडा जैसे छोटे-छोटे उपग्रहों का असर किस हद तक और कब तक होता हैं और इनका रुख राजनीतिक दल के प्रति कैसा रहता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर अपने राजनीतिक नेतृत्व पर संदेह करनेवाली हरिजनों की युवा पीढ़ी उग्रवादी संगठनों की ओर लपकी जा रही है, यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप से कांग्रेसी हुकूमत में हुए दमन की यह खतरनाक प्रतिक्रिया है। गांवों की हरिजन युवा पीढ़ी विपक्ष को तो घास नहीं ही डाल रही, क्योंकि वह अच्छी तरह समझती है कि उनके गुस्से के ताप को सहकर-पचाकर विपक्षी दल आंदोलन खड़ा करने या किसी किस्म के बदलाव लाने की कूवत नहीं रखता। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ उबल रहे अपने आक्रोश को विपक्ष को न सौंपकर भूमिगत उग्रवादी संगठनों और आई०पी०एफ० जैसे संगठन को सौंप रहे हैं। हरिजनों की नयी पीढ़ी अब नक्सली नेता विनोद मिश्र या फिर नागभूषण पटनायक जैसे नेतृत्वों पर ज्यादा एतबार कर रही है। यही वह खतरनाक परिवर्तन है जो दलित राजनीति में राजीव गांधी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पर राजीव अभी इस खतरनाक बदलाव से बेखबर या यों कहें कि लापरवाह दीख रहे हैं, इसलिए दलित नेतृत्व आज सही मायने में भूमिगत माहौल में हाथ-पांव फैला रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी पर से तो दलितों का भरोसा कब का उठ चुका है, क्योंकि कई दशकों में दलितों ने अनुभव से यही सीखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वे बस जुलूस की बेवजह कतार भर हैं।

बहरहाल, इतना जरूर है कि पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी की पीढ़ी का हरिजन कांग्रेस के साथ कमोबेश है, पर राजीव गांधी की पीढ़ी का हरिजन राजीव गांधी के साथ नहीं है। यह पीढ़ी विनोद मिश्र, डा० विनयन और नागभूषण पटनायक जैसों के पीछे है।

छाया : प्रभाकर
छाया : दीपक कुमार

—विकास कुमार

साक्षात्कार/**रामबिलास पासवान** अध्यक्ष, दलित सेना

'हमें दया का नहीं, ईर्ष्या का पात्र बनना है'

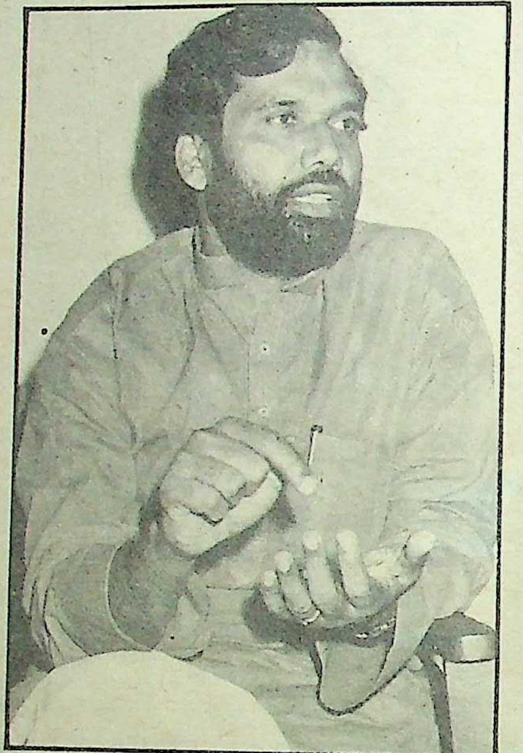

जब तक दलित नेतृत्व को अपनी दीनता पर गुस्सा नहीं आयेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व में दलित के लिए कोई जगह नहीं बनेगी। दलित नेतृत्व को जब इस बात का अहसास होगा कि हमें दया का नहीं, ईर्ष्या का पात्र बनना है, तभी बात बन सकती है।

माया: राष्ट्रीय राजनीति में दलित नेतृत्व बिलकुल कमजोर नजर आ रहा है। आखिर चूक कहां हुई है?

पासवान: हुकूमत के अंत:पुर में चाकरी करने के लालच ने आज दलित नेतृत्व को गर्त में पहुंचा दिया है। संसद में जब अपने मालिक को खुश करने के लिए के०के० तिवारी ने रामधन को 'चमार का बच्चा' कहा, तो ज्यादातर कांग्रेस के दलित-हरिजन सांसद ही कहने लगे कि रामधन को ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए संसद तक में जब दलित सांसद बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, तो राष्ट्रीष राजनीति में दलित नेतृत्व की बेचारगी पर बहस ही बेमानी है। जब तक दलित नेतृत्व को अपनी दीनता पर गुस्सा नहीं आयेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व में दलित के लिए कोई जगह नहीं बनेगी। दलित नेतृत्व को जब इस बात का अहसास होगा कि हमें दया का नही, ईर्ष्या का पात्र बनना है, तभी बात बन सकती है। सम्मान खोकर सत्ता से जुड़ने के आकर्षण ने ही नेतृत्व को पनपने नहीं दिया।

माया: यह तो नेतृत्व का रवैया है, पर आमतौर से सभी चुनावों में हरिजन मतदाता भी सत्ताधारी दल की पाली में चला जाता है। ऐसा क्यों?

पासवान: इसका उत्तर मैं हाल के अपने एक अनुभव से देना चाहूंगा। पिछले दिनों मैं पटना के कुछ हरिजन मुहल्लों में गया। वहां मैंने देखा कोई बच्चों का स्कूल तो नहीं, अलबत्ता भव्य मंदिर जरूर बने हुए हैं। मैंने वहां के हरिजनों से इस सिलसिले में जिज्ञासा की, तो उन लोगों ने बताया कि अपने पैसें खर्च कर मंदिर हम इसलिए बनाये हुए हैं, ताकि प्रशासन हमारा घर-द्वार उजाड़ न सके। आमतौर पर इंदिराजी या राजीव गांधी के नाम पर बहुत से हरिजन-मुहल्लों के नाम देखने को मिलते हैं। इसके पीछे बस एक ही भावना है कि इन 'नामों के रहने पर हम उजड़ नहीं सकेंगे। इस तरह हर पल खतरों और आशंकाओं से थका हुआ आम दलित भी चुनावों में सत्ता की पाली में चला जाता है। यह स्वेच्छा का नहीं घोर विवशता का 'सद्भाव' है।

माया: सत्ता से जुड़ा दलित नेता आम दलित से उदासीन है और विपक्ष का दलित नेता प्रभावहीन। ऐसे में दलित नेतृत्व किस घाट लगेगा?

पासवान: दरअसल, दलितों में वैचारिक प्रशिक्षण आज तक हुआ ही नहीं। नतीजतन, कांग्रेस से इतर होकर जब कभी विपक्षी मंच से कोई दलित नेता निकला, तो कांग्रेस ने उसे खरीद लिया। बी०पी० मौर्य जैसे नेता भी खरीदे गये। कांग्रेस ने मुझे भी खरीदने की कम कोशिश नहीं की। दलितों में सकट है नेतृत्व पर विश्वास का। आम दलित को यह भरोसा नहीं कि उसका नेता बहकेगा नहीं। सत्ता की बोटी पाकर वह कभी भी रंग बदल सकता है। चाहे कांग्रेसी सरकार हो या उन प्रांतों में जहां गैरकांग्रेसी सरकारें चल रही हैं, कहीं भी हरिजन खुशहाल नहीं। सच यही है कि इस देश में सरकारें बदली जा सकती हैं, धर्म बदले जा सकते हैं पर जाति नहीं बदली जा सकती। लिहाजा, दलित सर्वत्र दीन-दशा में हैं।

मीनाक्षीपुरम में जब एकमुश्त दलितों ने इस्लाम कबूल किया था, तो स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्यारह सांसदों की एक टीम वहां भेजी गयी थी। उस टीम में मेरे अलावा कांग्रेस की श्रीमती एम० चंद्रशेखर आदि भी थीं। मीनाक्षीपुरम में एक लड़का हमें मिला, नाम था हनीफ। उसने बताया कि उसका नाम पहले सुबय्या था। धर्म परिवर्तन की वजह पूछने पर उसने सभी सांसदों के संग एक बूढ़े हरिजन को लगा दिया और बोला कि अगर इसे आप यहां की चाय की दुकान पर चाय पिलवा दें, तो मैं मान लूंगा कि सचमुच आप हरिजनों के लिए कुछ करने में सक्षम हैं। बहरहाल, चाय की दुकान पर हम सब पहुंचे। श्रीमती एम० चंद्रशेखर ने चाय दुकानदार से कहा कि इस बूढ़े को भी चाय दो। चायवाला साफ इनकार कर गया। उसने कहा जब तक यह अपना बर्तन नहीं लायेगा, इसे चाय नहीं मिल सकती। अगर अपने कप में मैंने इसे चाय दे दी, तो कल से लोग मेरी चाय पीना बंद कर देंगे। फिर वह लड़का हनीफ आया। उसके लहजे में व्यंग्य था, हंसकर बोला कि जब आप ग्यारह एम०पी० मिलकर एक बूढ़े को चाय नहीं पिलवा सके, तो आप हरिजनों के लिए और क्या कर सकते हैं? सचमुच वह क्षण स्तब्ध कर देनेवाला था। ऐसी सडी हुई सामाजिक व्यवस्था में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। दलित नेतृत्व को इसे ढहाने के लिए पूरे मन से कमर कसनी होगी। दलित आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। नाथद्वारा में क्या हुआ? इसलिए आज दलित वर्ग यह सोचने को मजबूर है कि हम हिंदू हैं या नहीं। या हमें हिंदू बने रहना चाहिए या नहीं।

माया: देश की राजनीति में हरिजन का किनसे कारगर समीकरण बन सकता है?

पासवान: दलितों का समीकरण अल्पसंख्यकों, ईसाइयों, पिछड़े वर्गों और सिखों से कारगर बन सकता है। जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर सिख धर्म स्वीकार किया, वे आमतौर से ऊंची जाति के नहीं थे। केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह को ही लें, वह जाति से मेहतर हैं।

दरअसल जिस किसी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारने का साहस किया, उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहने का मेरा मकसद ब्राह्मण जाति से नहीं है। कोई दलित भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हिमायती हो सकता है और कोई ब्राह्मण भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोधी। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण होते हुए भी खोखले पाखंडों के सख्त विरोधी थे।

भगवानवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्म और जातिवाद यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। यह जब तक नहीं टूटेगी, दलित उठ नहीं सकेंगे।

माया: 'जनमोर्चा' के संयोजक रामधन भी दलित वर्ग से हैं। क्या दलितों में जागरण लाने की उनसे उम्मीद की जाये?

पासवान: जिसके पास खड़े होने की अपनी जमीन नहीं, वह कुछ भी हो जाये, कुछ नहीं कर सकता। दफ्तर और चपरासी मिल जाने से जनसमर्थन नहीं मिल जाता। वैसे 'जनमोर्चा' का जब कभी जिक्र भी आता है, तो रामधन का नाम तो वहां आता नहीं।

—विकास कुमार झा

जीवन के रंग अजीब...

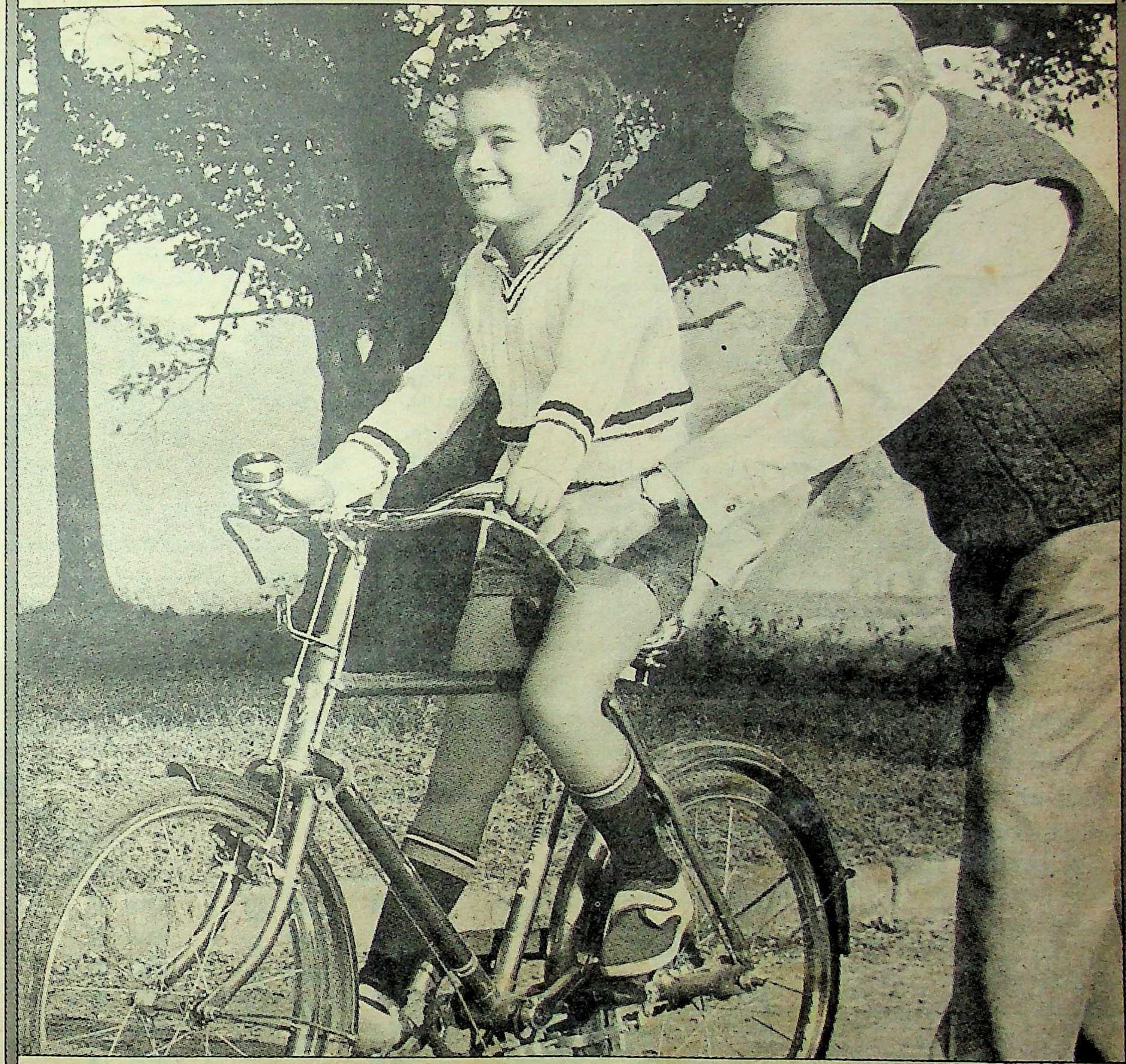

शुक्र है बोरोलीन करीब

खुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

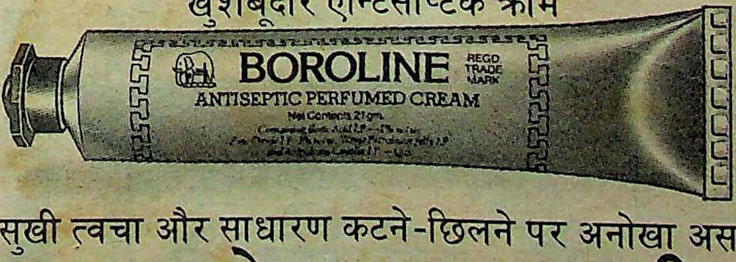
BOROLINE
REGD TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM
Net Contents 21 gm

सुखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

GD

जी डी फार्मास्युटिकल्स

कलकत्ता ७०००५३

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

Response 1038

अब

कौशम्बी स्कीम में अपार्टमेन्ट लेने का अद्वितीय अवसर

गाज़ियाबाद का दिल्ली की ओर प्रसार – अनेक प्रकार से।

निकटता : सोचिए ! इस अवस्थान से कार में आप पाँच मिनट में दिल्ली पहुँच सकते हैं।

स्थापन : दिल्ली के आई.टी.ओ. से केवल 10 कि.मी. की दूरी पर। दिल्ली के पूर्ण विकसित क्षेत्र के साथ स्थित।

आधुनिकता : दिल्ली में भी शायद आपको इससे बेहतर प्रस्ताव न मिले। बिल्कुल आधुनिक आकृति के भवन। पार्किंग की सुविधाऐं। खुली जगह व हरियाली। स्वस्थ वातावरण, शाँतिपूर्ण माहौल।

सुविधायें : जरूरत की सब सुविधाओं के अतिरिक्त एक बाजार व व्यापार केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। एक स्कूल व कालोनी क्लब का निर्माण भी प्रस्तावित है।

शुरू मे 800 इकाइयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। ज्यादा मांग होने पर इस संख्या को बढाया जायेगा।

नोट : भूतल के नक्शे इस योजना के लिए छपी पुस्तिका में उपलब्ध है।

प्राथमिकता : चिट्ठी डालकर अलॉटमेंट निम्नलिखित श्रेणियों से की जायेगी।

अपार्टमेन्ट्स का विवरण

संख्या	विवरण	संवत क्षेत्र	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण राशि
1.	एक कमरा (अपार्टमेंट)	220 वर्ग फुट	75,000	5,000
2.	ड्राइंग डाइनिंग व एक कमरा (अपार्टमेंट)	650 वर्ग फुट	2,60,000	25,000
3.	दो कमरे (अपार्टमेंट)	912 वर्ग फुट	3,65,000	35,000
4.	तीन कमरे (अपार्टमेंट)	1220 वर्ग फुट	4,75,000	45,000
5.	चार कमरे (अपार्टमेंट)	1445 वर्ग फुट	6,00,000	60,000

श्रेणी I: कौशम्बी योजना में पंजीकृत व्यक्ति अपना पंजीकरण इस योजना में परिवर्तित कर सकते है। 25% इकाइयाँ इस श्रेणी के लिए सुरक्षित हैं।

श्रेणी II: जी.डी.ए. की अन्य योजनाओं में पंजीकृत व अलॉटमेन्ट की प्रतीक्षा करते व्यक्ति भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। 25% इकाइयाँ इस श्रेणी के लिए सुरक्षित है।

श्रेणी III: 50% इकाइयाँ सामान्य श्रेणी के लिए सुरक्षित है। जी.डी.ए. ज़रूरत पड़ने पर इकाइयों की संख्या बढ़ाकर सब आवेदकों की माँग पूरी करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। पहले ड्रॉ मे नाम न आने पर अन्य अलाटमेन्ट में आवेदक के लिए व्यवस्था की जायेगी। 20% इकाइयाँ हर श्रेणी में नकद राशि भरने वालों के लिए सुरक्षित हैं। 50% राशि पंजीकरण राशि के रूप में भरने वाले आवेदकों को उनकी श्रेणी मे प्राथमिकता प्राप्त होगी। विशेषता : जी.डी.ए. अंकित राशि के भीतर शीघ्रता पूर्वक निर्माण कर मूल्य बढ़ने से रोकेगा। अवस्थान पर कार्य प्रगति पर है व इच्छुक व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है। भवन 2½ वर्ष तक पूरे हो जायेंगे।

भुगतान की योजना : आवंटी को दो वर्ष के भीतर अपार्टमेन्ट की शेष राशि भरनी होगी। पहली किस्त ड्रॉ निकलने से एक माह पूर्व जमा करनी होगी। जी.डी.ए. आवेदकों को आवासीय वित्त संस्थाओ से सहायता प्राप्त करने मे सहयोग देगी।

आवेदन कैसे करें : आवेदन पत्र निम्नलिखित बैंकों की किसी भी शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं आवेदन पत्र का मूल्य रु. 20/- होगा। पंजीकरण 26 जनवरी से शुरू होकर 29 फरवरी को समाप्त होगा। इसमे वृद्धि नहीं की जायेगी।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स : गाजियाबाद : शास्त्री नगर, राजपुरा शाखा व राइट गंज, कन्या वैदिक स्कूल के समीप। नई दिल्ली – एच-ब्लाक, कनॉट प्लेस व दरिया गंज शाखा। कलकत्ता : 25, ब्राबोर्न रोड व गिरीश पार्क। बम्बई : फोर्ट शाखा व 212, एस.वी. रोड, अन्धेरी व लोगेन्दरा रोड, दादर। मद्रास : माऊन्ट रोड। बैंगलोर : जे.सी. रोड। **भारतीय स्टेट बैंक :** हुसैनगंज, लखनऊ। **बैंक ऑफ इण्डिया** सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।

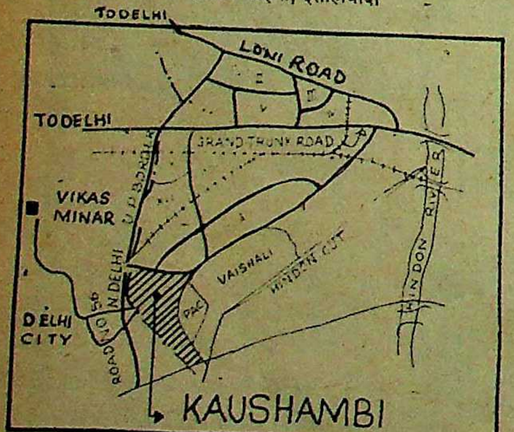

प्रभुनाथ मिश्र
उपाध्यक्ष

दिनेश चन्द मिश्र
सचिव

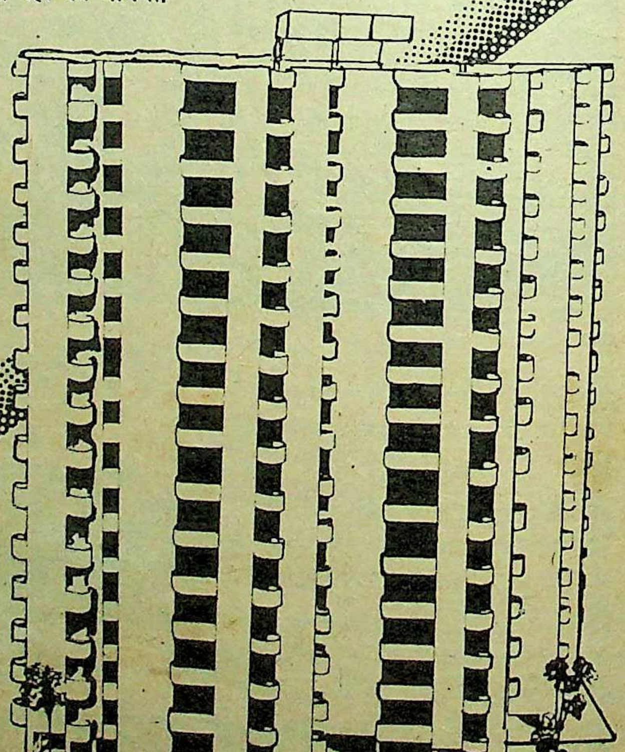

* जो व्यक्ति विदेश या दूरवर्ती कार्यरत है,
वे 31 मार्च 1988 तक
पंजीकरण करा सकते है।

**गाजियाबाद
विकास
प्राधिकरण**

Vidit

जवाबी मुहिम : शिवसेना एवं छत्रपति सेना के विरुद्ध दलित संगठनों का प्रदर्शन

रिडिल्स आफ हिंदुइज्म

मराठा और दलितों के बदले हुए तेवरों के आसार !

'बाबासाहब अंबेदकर साहित्य' के चतुर्थ खंड का विमोचन करते समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण को सपने में भी आभास नहीं था कि यही पुस्तक उनके गले की फांस बन जायेगी और महाराष्ट्र के मराठा और दलितों का तीन दशक पुराना बैर नया रूप धारण कर लेगा और वे तलवार भांजते हुए एक-दूसरे के सामने आ खड़े होंगे, राजनेताओं की बन आयेगी, सो ऊपर से। प्रस्तुत है, सारे विवाद का लेखा-जोखा :

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाबासाहब अंबेदकर की कृतियों के पांच खंडों के १९८० में प्रकाशन के निर्णय के तहत चौथे खंड 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म' का प्रकाशन १९८७ में हुआ जिसका विमोचन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण ने २ अक्तूबर '८७ को नागपुर में किया। 'इंडियन एक्सप्रेस' के सहयोगी प्रकाशन मराठी दैनिक 'लोकसत्ता' के संपादक माधव गडकरी ने अपने स्तंभ 'चौफेर' में इस चौथे खंड 'रिडल्स आफ रामा ऐंड कृष्णा' अध्याय में भगवान राम और कृष्ण के चरित्र पर बाबासाहब अंबेदकर द्वारा लगाये गये लांछनों की कड़ी आलोचना की और नवंबर के मध्य में इन अंशों के सार-संक्षेप प्रकाशित किये, तो इस चतुर्थ खंड के विरुद्ध विवाद शुरू हो गया।

जिस समय श्री गडकरी का लेख प्रकाशित हुआ, अमरावती में मराठा महासंघ का अधिवेशन चल रहा था, इसकी व्यापक प्रतिक्रिया अधिवेशन में हुई। महासंघ के अध्यक्ष शशिकांत पवार तथा क्रुद्ध कार्यकर्ताओं ने 'रिडल्स आफ हिंदुइज्म' की प्रतियां जलायीं। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जब नागपुर विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तो महासंघ के १० हजार से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। देवी-देवताओं की निंदा के विरुद्ध छत्रपति सेना तथा शिवसेना ने भी जलूस

निकाल कर प्रदर्शन किये और शिक्षामंत्री राम मेघे से चतुर्थ खंड से 'आपत्तिजनक अंश' निकालने की मांग की।

चतुर्थ खंड की महाराष्ट्र सरकार ने कुल १५ हजार प्रतियां छापी थीं, जिनमें से ५ हजार प्रतियां या तो बिक चुकी थीं या पुस्तक विक्रेताओं को बेचने के लिए दे दी गयी थीं। शिक्षामंत्री राम मेघे ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण से विचार-विमर्श कर पुणे स्थित सरकार के मुख्य बिक्री डिपो को अनबिकी सारी प्रतियां वापस ले लेने का मौखिक आदेश दिया और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चतुर्थ खंड से विवादास्पद अंशों को निकाले जाने की सूचना दी, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया तुरंत समूचे महाराष्ट्र में दलित वर्ग से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के दोनों गुटों (गवई एवं खापर्डे गुट) में हुई और वे दो दशक पुराने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक नये मोर्चे के तहत एक मंच पर एकत्र हो गये और व्यापक आंदोलन छेड़ देने की धमकी दी।

आंदोलन का कारण : आंदोलन को तीव्र हवा दी बाबासाहब अंबेदकर ग्रंथ समिति के संपादक मंडल के दलित कवि अरुण कांबले और प्रो० भालचंद्र फड़के ने इस्तीफा देकर। अरुण कांबले की १९८२ में प्रकाशित विवादास्पद कृति 'रामायणातील सांस्कृतिक संघर्ष' ने इसके प्रकाशन के समय ही काफी हंगामा बरपा किया था। प्रो० फड़के दलित साहित्य के कीर्ति स्तंभ माने जाते हैं। तीसरे संपादक एस०एस० रेगे का कहना था, "चूंकि यह अंबेदकर की मूल कृति है, इसलिए इसे हटाना नहीं चाहिए।" अरुण कांबले के विरुद्ध बंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा भी चला।

'संप्रदायवादियों के सामने घुटने टेक देने' के लगे आक्षेप, दिनोंदिन बढ़ रहे दलित-आंदोलन तथा ६ दिसंबर को बाबासाहब अंबेदकर के परिनिर्वाण एवं जन्म दिवस पर समूचे महाराष्ट्र के अलावा देश में विशाल आंदोलन की धमकी ने चह्वाण प्रशासन को विवादास्पद अंशों को निकालने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से मिली खुफिया रिपोर्टों ने भी जन-आंदोलन के हिंसात्मक मोड़ लेने की संभावना प्रकट की तथा इस मसले को निपटाने के लिए पुनर्विचार करने की सिफारिश की। फलतः मुख्यमंत्री ने विवादास्पद अंशों को हटाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की घोषणा की। समिति ने इसे अपनी विजय मानते हुए ६ दिसंबर के प्रस्तावित आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन 'विजय दिवस' के रूप में अपने शक्ति-प्रदर्शन के लिए १२ लाख अनुयायियों को चैत्य-भूमि (दादर, बंबई) पर एकत्र करने का निर्णय किया लेकिन आये मुश्किल से ७५ हजार अनुयायी।

चह्वाण सरकार की हिचकिचाहट ने शिवसेना, छत्रपति सेना, भीम सेना और मराठा महासंघ को क्रुद्ध कर दिया। इसके विरुद्ध अ०भा० मराठा महासंघ ने २९ नवंबर '८७ को महाराष्ट्र के ३० जिलों के कार्यकर्ताओं का एक बृहत सम्मेलन बंबई में आयोजित किया और मुख्यमंत्री चह्वाण की दलितों के सामने झुक जाने की तीव्र भर्त्सना की। मराठा महासंघ के अध्यक्ष शशिकांत पवार ने 'माया' को बतलाया, "मैंने उन्हें (रिपब्लिकन पार्टी एवं दलित संस्थाओं) पहले ही चेता दिया था कि वह इसे अपनी 'विजय' नहीं मानें। हम बाबासाहब अंबेदकर के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह किसी धर्म के देवी-देवताओं पर आक्षेप करें। उन्हें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन पर लांछन लगाने का हक उन्हें इसलिए नहीं मिल जाता कि वह समाज सुधारक या नेता थे। हम तो तब समझते जब वह कुछ कट्टर धर्म अनुयायियों के धर्म संस्थापकों के बारे में भी कुछ बोलने की हिम्मत करते। हिंदू धर्म उदार है, इसीलिए हर कोई बोलने का अधिकार पा लेता है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इन आक्षेपवाले अंशों को हटा नहीं देती। जरूरत पड़ी, तो हम अदालत का भी दरवाजा खटखटायेंगे। चेंबूर (बंबई) के सुहास अनंत जोशी बंबई उच्च न्यायालय में दिसंबर में 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म' के विवाद को निपटाने के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं।

पुस्तक विरोधी : बालठाकरे (बायें), शशिकांत पवार

शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का कहना था, "यदि वे (रिपब्लिकन पार्टी व दलित वर्ग) समझते हैं कि सिर्फ भीड़ एकत्र कर सरकार को मनमाने तौर पर झुकाया जा सकता है या दलितों के मोर्चे में आनेवालों की संख्या को भांप कर ही सरकार उनके सामने झुकना चाहती है, तो हम उनसे सौगुनी भीड़ वाला मोर्चा निकाल कर अपनी क्षमता दिखला सकते हैं। अगर सरकार देवी-देवताओं पर लगाये गये लांछनों को नहीं निकालेगी, तो शिवसेना विशाल आंदोलन छेड़ देगी, 'जेल-भरो' आंदोलन भी चलायेगी। यदि सरकार इस विवाद को जारी ही रखना चाहती है, तो उसे मोहम्मद पैगंबर के विवादास्पद अंशों तथा कवि कुसुमाग्रज की कविता 'सर्वात्मिका सर्वेश्वरा' को भी पाठ्य-पुस्तकों में शामिल करना पड़ेगा। आजकल यह फैशन चल पड़ा है कि हिंदू की निंदा करनेवाला प्रगतिवादी कहा जाता है और समर्थन करनेवाला प्रतिक्रियावादी।" (हजरत मुहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक अंशों, कवि कुसुमाग्रज की कविता 'सर्वात्मिका सर्वेश्वरा' तथा बी०बी० शिखाडकर की कविता 'सर्वात्मिका शिवा-सुंदरा' के विरुद्ध आंदोलन छिड़ने पर महाराष्ट्र शासन ने इन्हें विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से निकाल दिया था।)

बाल ठाकरे की इस टिप्पणी पर बाबासाहब अंबेदकर के प्रपौत्र तथा रिपब्लिक पार्टी के नेता प्रकाश अंब्रेदकर ने 'माया' को बतलाया, "ऐसे में फिर सरकार को वाल्मीकि रामायण, महात्मा ज्योतिबा फुले, भास्कर जाधव, प्रो० दामोदर कोसांबी, गोपाल गणेश आगरकर, राजाराम शास्त्री भागवत, लोखितवाडी, गोपालराव देशमुख के कथनों को भी हटाना पड़ेगा। और-तो-और बाल ठाकरे के पिता प्रबोधंकर ठाकरे ने भी हिंदू धर्म के विरुद्ध काफी कुछ लिखा, प्रो० भास्कर राव जाधव से लेकर गोपाल राव देशमुख तक ने भी काफी कुछ हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध लिखा, लेकिन तब क्यों नहीं हंगामा हुआ ?"

आंदोलन के संकट को टालने के लिए शिक्षामंत्री राम मेघे ने 'रिडिल्स आफ रामा ऐंड कृष्णा' को बाबासाहब की अप्रकाशित रचना मानी, कुछ ने इसका फायदा उठाकर इसे 'उनके अनुयायियों द्वारा लिखा और जोड़ा गया अंश' की आशंका भी प्रकट कीं, लेकिन डा० अंबेदकर की पत्नी माई अंबेदकर ने यह कह कर इन सारे ऊहापोहों को खतम कर दिया कि 'ये अंश

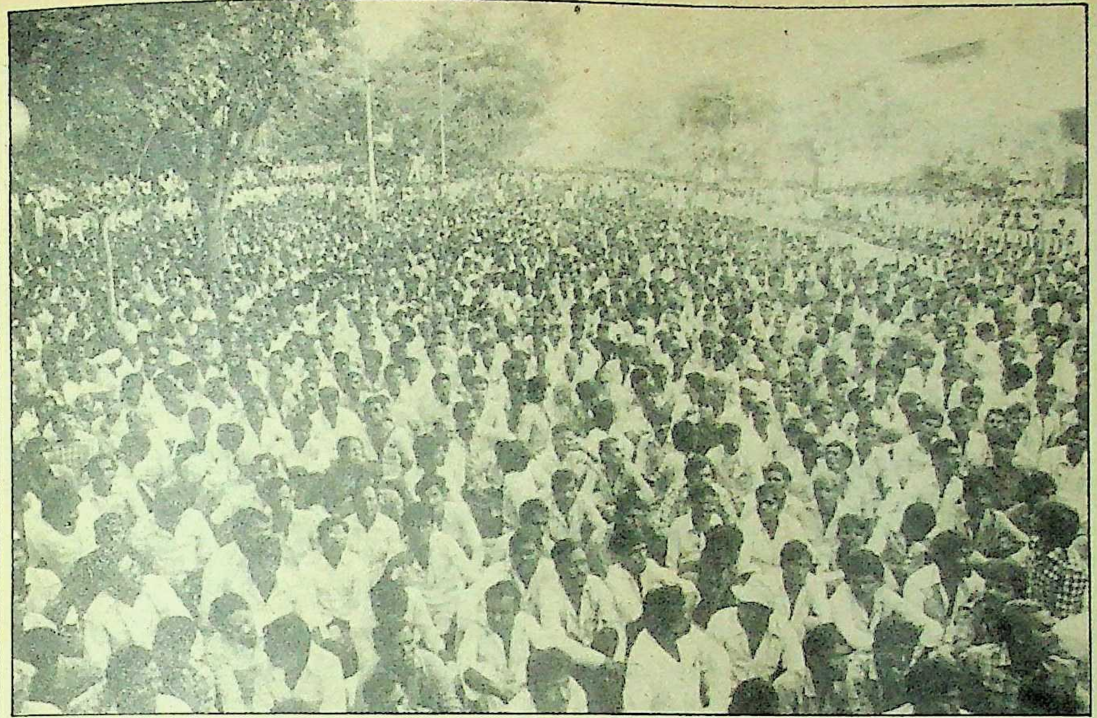

अंश निकालने के विरुद्ध : दलित पैंथर मोर्चा

> महाराष्ट्र सरकार
> की जान सांसत में फंसी
> है। अगर पुस्तक से विवादास्पद अंश निकालते हैं, तो प्रकाश अंबेदकर उसे दिये गये प्रकाशन-मुद्रण के अधिकार को वापस लेकर खुद उसे प्रकाशित करेंगे। अगर विवादास्पद अंश नहीं निकालते, तो शिवसेना से लेकर मराठा महासंघ—सभी दल फरवरी-मार्च में
> विशाल आंदोलन
> छेड़ देंगे।

बाबासाहब के ही लिखे हुए हैं और इन पांडुलिपियों को मैंने देखा और पढ़ा है।'' डा० अंबेदकर की हस्तलिपि के विशेषज्ञ बी०एम० चिटणीस ने भी 'रिडिल्स आफ रामा ऐंड कृष्णा' की पांडुलिपि की जांच कर उसे डा० अंबेदकर का ही लिखा घोषित किया। बाबासाहब अंबेदकर ग्रंथ संपादन समिति के एक सदस्य अरुण कांबले, जिन्होंने विवाद के तुरंत बाद त्याग पत्र दे दिया था, बंबई उच्च न्यायालय में दायर कर प्रार्थना की कि 'विवादास्पद अंशों' को निकाला न जाये।

विमोचन : २ अक्तूबर को मुख्यमंत्री चह्वाण ने नागपुर में एक विशेष समारोह में जब 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म' का विमोचन किया, था और प्रकाशन निदेशालय को ५ वां खंड भी शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर देने का निर्देश दिया था तब उन्हें पता नहीं था कि आगामी कुछ ही दिनों के भीतर उनकी जान सांसत में फंस जायेगी। यद्यपि शिवसेना सहित रिपब्लिकन पार्टी ने भी उलटे उन पर ही आरोप लगाया कि वह जानबूझकर इसे विवाद का रूप देना और इसे लटकाये रहना चाहते हैं, ताकि फरवरी में होने वाले जिला परिषद चुनावों के पूर्व अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और दलितों तथा सवर्णों को भरमाये रख कर सौदेबाजी कर सकें। प्रकाश अंबेदकर का कहना था, ''सरकार इसे राजनीतिक रंग देना चाहती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के पहले हिंदुओं का हौवा खड़ाकर अल्पसंख्यकों के वोट हथियाये जाते रहें, अब प्रतिक्रियावादी ताकतें सामने आ खड़ी हुई हैं और लोग उनका 'राजनीतिक भुगतान' करने पर जुटे हुए हैं।

गहराता विवाद : १९५६ में बाबासाहब अंबेदकर के निर्वाण के बाद उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में चला गहरा विवाद अदालत तक जा पहुंचा। एक तरफ उनकी चल-अचल संपत्ति, जिसमें हिंदू कालोनी (दादर) स्थित शानदार मकान भी था, का सवाल था तो दूसरी तरफ उनका बृहत साहित्य था, जिसमें बहुत-सी रचनाएं अप्रकाशित थीं। उनके नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के अनुयायियों ने, जिनकी संख्या हजारों में थी, अपने अधिवक्ता जे०बी० बनसोड के माध्यम से उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच में एक याचिका दायर की, इसमें महाराष्ट्र शासन, सौ० सविता अंबेदकर, भैया साहब यशवंतराव अंबेदकर को पार्टी बनाया गया। औरंगाबाद के बाबासाहब अंबेदकर के एक कट्टर अनुयायी तथा दलित पैंथर नेता ने 'माया' को बतलाया, ''बाबासाहब की मौत के बाद से ही उनकी चल-अचल संपत्ति को लेकर खींचतान और मुकदमेबाजी शुरू हो गयी थी। उनके परिवार के लोगों को उनकी संपत्ति से मतलब था, इसलिए वे उनके साहित्य के प्रकाशन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हम निरंतर मांग करते रहे और वे लोग टालते रहे, फलतः १९७६ में हमने उन्हें स्पष्टतः चेतावनी दी कि अगर वे उनके साहित्य के प्रकाशन में दिलचस् नहीं रखते, तो हमें दे दें। हम उनका सस्ता संस्क छपवाकर समूचे साहित्य को घर-घर पहुंचायें पहले महाराष्ट्र में फिर पूरे देश में। हमारी योज शुरू में इसे अंग्रेजी (उन्होंने अधिकांश रचन अंग्रेजी में ही लिखी थीं) और मराठी में, फिर दूस भाषाओं में इनके अनुवाद छापने की थी, लेकि उनके परिवारवालों ने कोई ध्यान नहीं दिया।''

इस प्रकरण के बारे में बाबासाहब के प्रपौ ३२ वर्षीय एडवोकेट प्रकाश अंबेदकर जो बाब साहब की पत्नी माई अंबेदकर के साथ उनके मका में रहते हैं और उनके मुख्य वारिस तथा रिपब्लिक पार्टी के नेता हैं, का कहना था, ''यह सही है f संपत्ति के विवाद को लेकर मेरे दादा और पिता मतभेद रहा और यह मामला अदालत में भी गय था, लेकिन यह आरोप गलत है कि हमारा परिवा उनके साहित्य के प्रकाशन के प्रति उदासीन था दादाजी के निधन के बाद बंबई उच्च न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, बंबई को उनके साहित्य देखभाल का निर्देश दिया। तब से उनकी सा पांडुलिपियां सरकार के पास हैं, सिर्फ कापीराइ हमारे पास है। १९७६ में सरकार ने दादा प्रकाशन योग्य साहित्य की सूची तैयार करने के लि एम०वी० मून को विशेष अधिकारी नियुक्त किया मून द्वारा तैयार सूची को सरकार ने हमारे पा भेजा, तो हमने उस पर स्वीकृति दे दी और इन प्रकाशन तथा मुद्रण का अधिकार सरकार को सौं दिया। इनमें दादाजी के प्रकाशित-अप्रकाशि कृतियों के अलावा इनके भाषण, विचार तथ विभिन्न अवसरों पर की गयी टिप्पणियां थीं। इन से चार खंड प्रकाशित हो चुके हैं। पांचवां खंड अभ प्रकाशित होना है। प्रथम तीन खंडों में उनके विचा तथा भाषण हैं। चतुर्थ खंड छपने के बाद कुछ नह होता, संभवतः यह विवाद होता भी नहीं, अग 'लोकसत्ता' के संपादक माधव गडकरी, जो हमा मित्र भी हैं, इसके विरुद्ध नहीं लिखते और य टिप्पणी नहीं करते कि 'सरकार को हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह के लांछन लगानेवाले साहित् को नहीं छापना चाहिए।' बस सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ।''

प्रतिक्रियाएं : मराठी के एक प्रख्यात लेख एवं प्रखर पत्रकार ने अपना नाम न छापने क अनुरोध करते हुए 'माया' से बतलाया, ''बाबासाह को क्या अधिकार था किसी देवी-देवता की खिल्ली उड़ाने का। अगर हम उनके समग्र जीवन और वैचारिकता के ऊहापोह को उजागर कर छापने लगें तो समूचा दलित वर्ग और रिपब्लिकन पार्टी इसे 'अछूतों पर वैचारिक हमला' मानकर अहिंसक आंदोलन कर बैठेगा। मैंने जब भी बाबासाहब की विचारधाराओं की समीक्षा की, तो मुझे धमकिय मिलीं।''

मराठवाड़ा महासंघ के विशेष अधिवेशन में भाग लेने आये चंद्रपुर शहर के मराठा महासंघ के एक वयोवृद्ध कार्यकर्ता सा०हि० फड़के का कहना था, ''दलित वर्ग जानबूझकर शुरू से ही हंगामे खड़ा

रता रहा और राजनीतिक पार्टियां इसे कैश करती
ों। उन्होंने जानबूझ कर राजनीतिक दलों की
जिश के साथ, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का
म बाबासाहब अंबेदकर विश्वविद्यालय रखने का
दोलन चलाया। उन्होंने मराठवाड़ा विश्व-
द्यालय को ही क्यों शिकार बनाया? बंबई
श्वविद्यालय या नागपुर या पूना विश्वविद्यालय
ा नाम भी चुन सकते थे इसके लिए। मराठवाड़ा
त्र में बाबासाहब ने भला क्या किया था? वह
बई में रहे, नागपुर और पुणे को अपना कार्यक्षेत्र
ाया था। इन लोगों ने आदिवासियों को यह कह
र भड़काया कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हें सवर्णों से
ड़ कर अपना अधिकार छीनना चाहिए। ये लोग
दालत में जा सकते थे और शोषक सवर्णों के विरुद्ध
जदारी के मामले दाखिल कर सकते थे। हमने तो
य कर लिया है, अब बहुत हो चुका हिंदुत्व पर
मला, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमला
रने के पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, फिर
त कीजिए।"

बंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति
र०ए० जहांगीरदार तथा टी०डी० सुगला की
डपीठ में सुहास अनंत जोशी ने पुस्तक के प्रकाशन
ो रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। सुहास
ोशी की तरह एक दर्जन से भी अधिक मामले
भिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। महाराष्ट्र
रकार ने इस मामले में 'टालूपन' का रवैया
पनाया है। वैसे फरवरी १९८८ काफी गंभीर
हेगा, क्योंकि जिला परिषद चुनाव सभी दलों के
ए 'अस्तित्व का चुनाव' बन गया है और इसकी
णनीति 'जातिवाद की पराकाष्ठा' ही तय करने
ाली है। इसे कांग्रेस पार्टी ने भी समझ लिया है और
गवसेना, दलित संघ तथा दूसरी पार्टियों ने भी।

"लेकिन दलित बनाम मराठा विवाद में
सली दोषी को हमने छोड़ ही दिया," प्रखर
चारक सुधीर सावंत कहते हैं, "बाबासाहब की
गह अगर किसी ने इस तरह का आपेक्ष किया
ोता, तो उस पर देवी-देवता के चरित्र-हनन का
कदमा खुद सरकार चलाती। लेकिन धर्म-
रपेक्षता का दावा करने वाली वही सरकार जब
स तरह के विवादास्पद आक्षेपोंवाली पुस्तकें
ापती है, तो मुकदमा सीधे उस पर चलाया जाना
ाहिए था, आंदोलन उसके विरुद्ध होने चाहिए थे।
गर किसी प्रायवेट पब्लिशर ने इस तरह की
रकत की होती, तो यही सरकार उसे सींखचों में
द कर देती।"

लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जान सांसत में
सी है। अगर पुस्तक से विवादास्पद अंश निकालते
, तो प्रकाश अंबेदकर उसे दिये गये प्रकाशन-मुद्रण
 अधिकार को वापस लेकर खुद उसे प्रकाशित
रेंगे। अगर विवादास्पद अंश नहीं निकालती, तो
शिवसेना से लेकर मराठा महासंघ—सभी दल
रवरी-मार्च में विशाल आंदोलन छेड़ देंगे। और
स चक्कर में अब पांचवें खंड का प्रकाशन खटाई में
ड़ गया है।

—रवींद्र श्रीवास्तव

साक्षात्कार/ **प्रकाश अंबेदकर**

हम चैन से नहीं बैठने देंगे

जब से हाजी मस्तान ने बाबासाहब अंबेदकर के प्रपौत्र तथा उनके वारिस ३२ वर्षीय प्रकाश अंबेदकर में दलितों और दलित मुस्लिमों का एकमात्र नेता होने की संभावना देखी है तथा 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म'—प्रकरण में प्रकाश अंबेदकर ने प्रखर भूमिका निभायी है तब से वह अचानक सुर्खियों का विषय बन गये हैं। प्रकाश अंबेदकर अपने दादा डा० अंबेदकर के कट्टर अनुयायी हैं। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं और डा० अंबेडकर से संबंधित शिक्षा संस्थाओं तथा दूसरे संगठनों की देखभाल कर रहे हैं। वह पेशे से एड्वोकेट हैं। प्रस्तुत हैं, प्रकाश अंबेदकर से 'माया' की हुई बातचीत का सारांश:

माया: यदि महाराष्ट्र सरकार 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म' के विवादास्पद अंशों को निकालने के निर्णय पर अटल रहे तो?

प्रकाश: ऐसा नहीं होने देंगे हम। अगर सरकार को बाबासाहब के विचारों और लेखन को संशोधन के बाद ही छापना था, तो उसने यह करार क्यों किया कि वह उन्हें यथावत प्रस्तुत करेगी। अब वह लोगों के दबाव में आ कर अपने वादे से मुकर रही है, यदि उसने हमारी बात नहीं मानी, तो हम मार्च १९८८ में आंदोलन छेड़ देंगे जो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हम लाखों लोगों का मोर्चा लेकर बंबई में विधानसभा के आगे अनिश्चित कालीन धरना देंगे।

माया: क्या आंदोलन के बल पर आप अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे?

प्रकाश: आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत है। वह किसी एक की नहीं, पूरे देश और समाज की ताकत है। जब आंदोलन देश से अंग्रेजों को भगा सकता है, तो हम अपनी मांगें क्या अपनी ही सरकार से नहीं मनवा सकते।

माया: हिंदुओं में इसलिए रोष है कि राम-कृष्ण उनके आराध्य देवता हैं, क्या किसी धर्म पर कीचड़ उछालना आवश्यक है?

प्रकाश: हम किसी के धर्म को भला-बुरा नहीं कहते। जहां तक राम और कृष्ण के बारे में लिखी बात का प्रश्न है, इसका जवाब तो बाबा ही दे सकते थे। हरिजन भी हिंदू हैं और वे भी राम-कृष्ण को मानते हैं।

माया: क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि बाबासाहब अंबेदकर की सेवाओं का आपको उचित मुआवजा नहीं मिला, जबकि आज हर क्षेत्र में आप लोगों के लिए स्थान सुरक्षित हैं?

प्रकाश: बाबासाहब की सेवाओं का सरकार क्या मुआवजा देगी। वह तो वोट की राजनीति के लिए अपना धर्म-ईमान तक बेच देती है, दलितों ने संघर्ष किया, लेकिन उन्हें क्या मिला? हमारा संघर्ष ब्राह्मणशाही विरोधी है। हम चाहते हैं कि सरकार मजदूर, श्रमिक, कामगारों पर अत्याचार रोके और भूमिहीनों को भूमि दे।

माया: यदि कांग्रेस आपका सहयोग नहीं करती, तो फिर कौन-सी ऐसी पार्टी है जो आपके हितों की रक्षा कर सकती है?

प्रकाश: मैं किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं करता। सबके अपने-अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। यदि किसी पार्टी पर भरोसा होता, तो हम अपनी अलग पार्टी का गठन क्यों करते?

माया: हाजी मस्तान किन शर्तों पर आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं?

प्रकाश: इस बारे में हाजी मस्तान से हमारी कोई व्यक्तिगत बात नहीं हुई। उन्होने स्वयं समर्थन देने की घोषणा की है।

माया: देश के किन प्रांतों से आपको समर्थन मिल रहा है?

प्रकाश: हमें कर्नाटक, मद्रास, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दलितों का समर्थन मिला है। हाल ही के सम्मेलन में इन प्रांतों से आये लोगों ने शिरकत भी की है।

माया: यदि आपका आंदोलन महाराष्ट्र में सफल न हुआ, तो आप कौन-सा रास्ता अख्तियार करेंगे?

प्रकाश: हम अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन बतायेगा कि हम क्या हैं? सरकार हमारा आंदोलन खतम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने यह निश्चय कर लिया है कि हम हरसंभव किसी भी माध्यम का उपयोग कर सरकार की आंख खोलने की कोशिश करेंगे और सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हैं।

माया: लोगों का मानना है कि आपकी पार्टी आंदोलन कर प्रचार और सरकार का ध्यान अनावश्यक ही खींचना चाहती है।

प्रकाश: ऐसी बात नहीं है। हम सरकार को अनावश्यक तंग नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हम अपने हक के लिए न लड़ें, तो हम उपेक्षित ही होते रहेंगे? हमारा कुसूर क्या है?

—महादेव शर्मा

पुलिस और नक्सली आमने-सामने

तेवर खतरनाक हैं

क्या इस रोग का इलाज पुलिस है ?

आंध्र की घटना के बाद देश में नक्सलियों का खतरा एक बार फिर बढ़ चला है। सातवें दशक में शोषण और जुल्म के खिलाफ 'नक्सलबाड़ी' से शुरू हुआ नक्सलवादी आंदोलन उस समय तो किसी तरह कुचल दिया गया था, मगर उसकी चिंगारियां आसपास फैल गयीं और जिसने आज भयंकर रूप धारण कर लिया है। लेकिन यह आंदोलन अब भटक चुका है। वर्ग-संघर्ष की अवधारणा पर शुरू हुआ यह आंदीलन आज वर्ण-संघर्ष पर उतारू हो गया है और बीसियों गुटों में बंटे नक्सली अपने लक्ष्य को भूलकर धन उगाही में जुटे हुए हैं।

'रेड एलर्ट !' यानी पुलिस और नक्सली फ़िर आमने-सामने हैं। इस बार दोनों पक्षों के तेवर खतरनाक हैं। पूरी सरगर्मी और बेचैनी से पुलिस ने बिहार के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में दुंदुभि बजा दी है और नक्सली भी जवाबी तौर पर पुलिस को जता चुके हैं कि तैयारी उनकी भी पूरी है। जहानाबाद, गया और हजारीबाग जिले के चतरा क्षेत्र की सीमाएं सील कर दी गयी हैं। युद्ध स्तर पर अभियान जारी रखने के लिए बिहार सरकार ने पुलिस को हेलीकाप्टर भी सुलभ करा दिया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस, कोने-कोने पर खुफिया नजर।

आखिर इतनी चौकसी और चाक-चौबंद होने का सबब क्या है ? और क्या ये सारी तैयारियां नक्सली संगठनों पर काबू पाने के लिए काफी हैं ? इन बातों से बिहार के आम लोग उतने चिंतित नहीं जितने कि सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी। आम लोग इसलिए चिंतामुक्त हैं, क्योंकि पहले नक्सलियों के हाथ जब निरीह लोगों की जानें गयीं, तो कोई बावेला नहीं मचा। अब जबकि एक-एक कर पुलिसवाले नक्सली बंदूकों का निशाना बन रहें हैं, तो पुलिस बौखलायी हुई है और नौकरशाही परेशान है। आंध्र में नक्सलियों द्वारा आई०ए०एस० अधिकारियों के अपहरण की घटना ने बिहार की पुलिस और नौकरशाही को भीतर से सिहरा रखा है कि कहीं बिहार के शातिर नक्सली आंध्र से मिले फार्मूले का उपयनेग न कर बैठें ?

पुलिस पर हमला : २८ दिसंबर '८७ से ४ जनवरी, १९८८ के बीच बिहार में हजारीबाग से जहानाबाद तक जिस तरह नक्सलियों ने पुलिस को मौत के घाट पहुंचाने और शस्त्र लूटने का अभियान शुरू किया, उससे हुकूमत का सिहरना कतई अस्वाभाविक नहीं था। हजारीबाग के चतरा क्षेत्र के गारो जंगल में २८ दिसंबर को एम०सी०सी० (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर) और पुलिस के जवानों में काफी तेज टकराव हुआ। नतीजतन पुलिस के तीन जवान और वन विभाग के चार कर्मचारी घायल हुए। एक घायल पुलिस जवान हरी गोप ने रांची अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ दिया। दरअसल, एम०सी०सी० की सशस्त्रवाहिनी ने वन व्यापार निगम के ट्रकों पर बाहर भेजी जा रही लकड़ियों को जाने से रोका। इसी तनाव में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोली चल गयी।

पिछले कुछ समय से नक्सलियों की जमात चतरा के लोगों को इसके लिए जागृत कर रही है कि ऐसे में जबकि चतरा के लोग रोजी के बिना भूखों मर रहे हैं, चतरा के जंगलों की लकड़ी बाहर नहीं जाने दें। चतरा के प्रतापपुर, हंटरगंज, ईटखोरी आदि इलाकों में खैर का सघन वन है, जिससे बड़े पैमाने पर कत्थे की चुलाई होती है। जंगल के गरीब बाशिंदों की आजीविका का यही साधन था— कत्थे की चुलाई और जंगल की लकड़ी से होनेवाली आय। पर वन विभाग द्वारा पाबंदी लगने के बाद से चतरा के लोगों के सामने रोजी-रोटी की भयावह समस्या आ खड़ी हुई। नतीजतन, नक्सली जमात ने इसी को

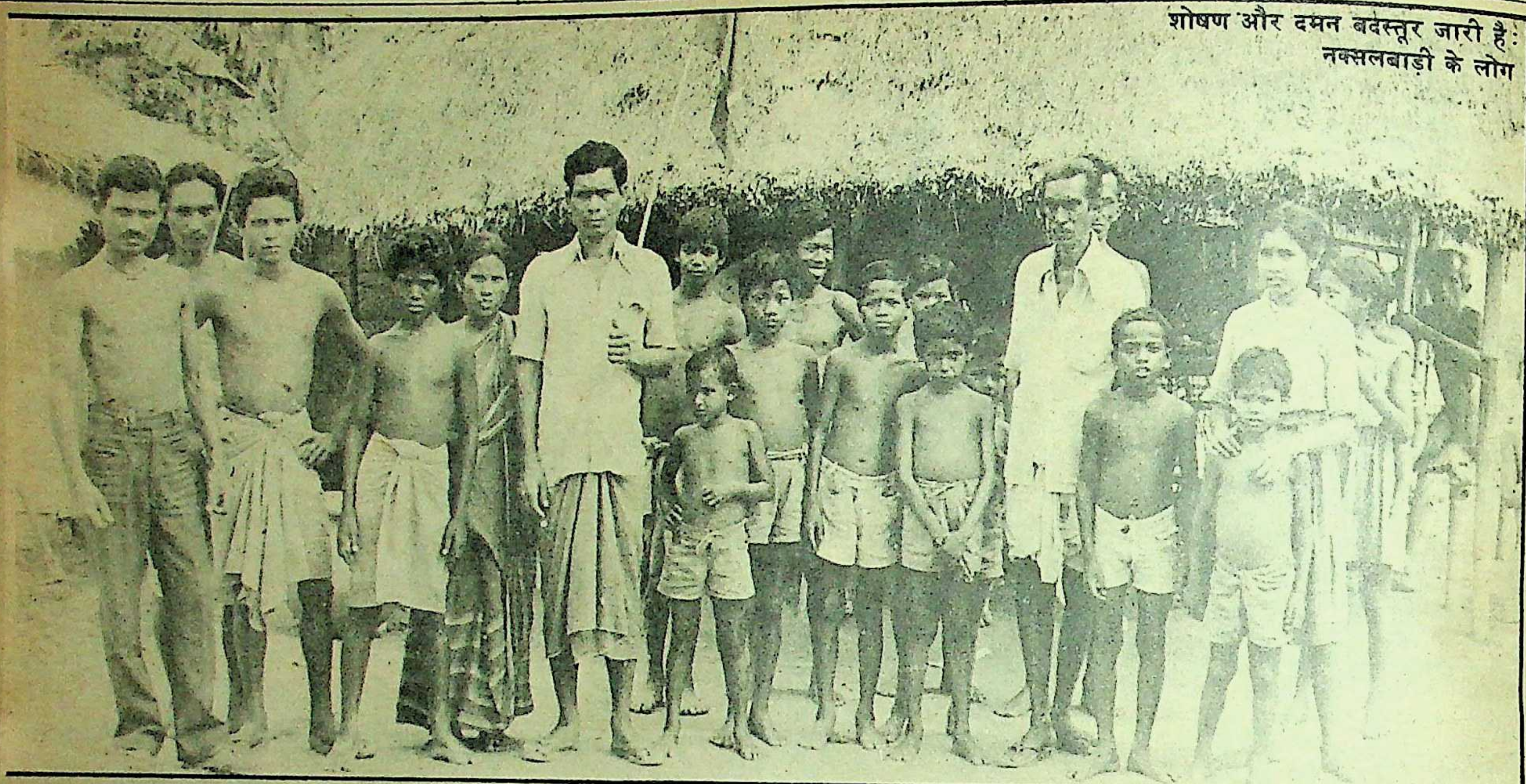

शोषण और दमन बदस्तूर जारी है: नक्सलबाड़ी के लोग

बीस साल बाद नक्सलबाड़ी !

आज जबकि फिर नये सिरे से देश में नक्सली गतिविधियों ने धूम मचा दी है, 'नक्सलवाद' की जन्मभूमि नक्सलबाड़ी की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। पूरे बीस साल गुजर चुके हैं नक्सलबाड़ी की उस ऐतिहासिक क्रांति को, जिसने देश के गांव-गांव में सामंती व्यवस्था के खिलाफ बेसहारों व शोषितों के हक को लेकर बिलकुल गुरिल्ला शैली के लड़ाकुओं के लिए एक विशेषण दिया 'नक्सलाइट'। आज बेसहारों-बेजमीनों के संघर्ष की वही प्रतीक भूमि, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा नक्सलबाड़ी बीतते वक्त के साथ वही गुरबत और विकास का मोहताज होकर बुरी तरह आहत है। आंदोलन की धुरी ही टूट कर रह गयी है।

"कौन देखेगा नक्सलबाड़ी की यह तबाही, नक्सलबाड़ी की तो मौत हो गयी"—कहता है नक्सलबाड़ी का बीरेश राय। बीरेश राय के पास इतनी जमीन भी नहीं कि उसे ही जोत-कोड़ कर वह अपने कुनबे के लिए दो जून की रोटी जुटा सके। अकेले बीरेश की ही यह दशा नहीं है। नक्सलबाड़ी की आधी से अधिक आबादी बेजमीन होकर बेरोजगारी का दंश झेल रही है।

"क्या किया इस ज्योति बसु ने और उसकी वाम सरकार ने नक्सलबाड़ी के लिए। न कोई कल-कारखाना, न कोई रोजी-रोजगार, न सिर छिपाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा। कुछ भी नहीं। जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचते हैं तो कभी रोटी मिलती है, कभी नहीं। उन लकड़ियों के तोड़ने पर भी अब आफत है।" यह चिका बर्मन है जो नक्सलबाड़ी की स्थिति की चर्चा करते-करते बिफरने लगता है।

सिलीगुड़ी से कुछ दूर स्थित नक्सलबाड़ी थाने की जनसंख्या लगभग डेढ़-पौने दो लाख है। मुख्य रूप से इनमें राजवंशी, मधेसिया, नेपाली, असमी, बंगलादेशी, मुसलमान, आदिवासी व थारू हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार के लोग भी काफी संख्या में इधर आ बसे हैं। राजवंशी, आदिवासी और थारू जीवन-यापन के लिए चाय बागान में मजदूरी करते हैं या खेती। राजवंशी पूर्वी बंगाल से आकर यहां बस गये हैं और इनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है।

१९७१ के बाद के दिनों में बंगलादेश के शरणार्थी और असमी बड़ी तादाद में यहां आ बसे। रोजगार का कोई साधन था नहीं। लिहाजा, तस्करी के धंधे को बहुत से लोगों ने अपनी रोजी-रोटी का साधन बना लिया। नेपाल की सीमा नजदीक होने के कारण और बिहार के पूर्णिया, कटिहार का क्षेत्र तथा जोगबनी समीप होने के कारण तस्करी करना यहां आसान था। नक्सलबाड़ी होकर तस्करी का सामान तथा मादक पदार्थ भूटान, दार्जिलिंग, गुवाहाटी और कलकत्ता आदि आसानी से निर्यात किया जाता है।

नक्सलबाड़ी का परशुराम कहता है, "गरीबी और भूख ने नक्सलबाड़ी को तस्करी का अड्डा बना दिया।"

१९६७ की क्रांति में तीन थानों नक्सलबाड़ी, फांसीदेवा और फोरीबाड़ी में चाय मजदूरों पर दमन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति हुई थी। आज भी इन तीनों थानों के लोग बेहाल घिसट रहे हैं। समस्याओं ने अपना शिकंजा इन निरुपाय लोगों पर और भी ज्यादा कस दिया है। नक्सलबाड़ी की नयी पीढ़ी को इसकी अतीत कथा अब अविश्वसनीय प्रतीत होती है। आज से दस साल पूर्व जिस नक्सलबाड़ी में एक भी भूमिहीन नहीं था, लेकिन आज बहुतायत में हैं। दरअसल, बंगलादेशी मूल के तथा अन्य लोगों ने तस्करी से अर्जित धन से नक्सलबाड़ी के गरीबों से कौड़ियों के मोल जमीनें खरीद ली हैं। इस तरह तस्करी के धन ने नक्सलबाड़ी की नन्ही अर्थव्यवस्था को भी तोड़ कर रख दिया।

एक-डेढ़ एकड़ जमीन की मिल्कीयत वाले किसान भी बमुश्किल तीस-चालीस प्रतिशत हैं। सिंचाई साधनों के अभाव में खेती भी हर साल चौपट हो जाती है। चेंगा, मंझा, बालासन और बतरिया नदी के जरिये सिंचाई-साधन आसानी से सुलभ कराया जा सकता है, पर किसे फिक्र और फुरसत है नक्सलबाड़ी के लिए? आखिर क्यों नक्सलबाड़ी की मिट्टी इतनी सर्द हो गयी है? जवाब में नक्सलबाड़ी का एक व्यक्ति कहता है, "जो मिट्टी देर से गर्म होती है, वह देर तक ठंडी भी रहती हैं।"

—विकास कुमार झा

प्राथमिक मुद्दा बनाकर अपनी मुहिम तेज की कि 'जंगल की संपत्ति से हम जियेंगे, कत्था और लकडी अपने लिए रखेंगे।' नक्सलियों ने जंगल के भूमिहीनों को उत्साहित कर बहुत से वन क्षेत्र को जोतने के लिए तैयार भी कर दिया। एम०सी०सी० ने वनों की कटाई के खिलाफ कई परचे छापकर प्रशासन को चेतावनी भी दी। साथ ही अपनी स्थिति और उपस्थिति का अहसास दिलाने के लिए एम०सी०सी० वालों ने पोरम गांव के पंचायत भवन को और हिंदिया स्थित वन विभाग के उस रेस्ट हाउस को, जहां पुलिस का पड़ाव था, फूंक डाला।

चतरा क्षेत्र से भाजपा विधायक महेंद्र सिंह भोगता ने 'माया' को बताया कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी गंझू लोगों की है जो हरिजन होते हैं और भोगता कहलाते हैं। आबादी में दूसरे नंबर पर भुइयां हैं। ये गंझू और भुइयां गरीबी के आखिरी सिरे से किसी तरह लटक रहे हैं। नतीजतन, इनके दमन को आधार बनाकर नक्सलियों को अपना कार्यक्षेत्र बनाने का उपयुक्त अवसर मिला। महेंद्र सिंह कहते हैं, ''स्थिति यह है कि ईटखोरी प्रखंड के गिद्धौर पचायत का अस्पताल चिकित्सक के अभाव में दस वर्षों से बंद पड़ा है। ऐसी हालत में इलाके के अधिकांश अस्पताल हैं। लोग बीमार होते हैं और इलाज की कमी से दम तोड़ देते हैं। इसी तरह जजरी गांव में लीलाजन नदी का पुल १९७६ से टूटा पड़ा है, पर अब तक कुछ भी नहीं हो सका। सड़क और बिजली तथा बच्चों का स्कूल चतरा क्षेत्र के लिए सपना है। ऐसे माहौल में तो नक्सली पनपेंगे ही।''

रेड एलर्ट! चतरा के जंगल में पुलिस पत्ता-पत्ता छान रही है। हजारीबाग के इंका विधायक एच०एच० रहमानी कहते हैं, ''चतरा क्षेत्र में दूर-दूर तक नक्सली प्रभाव नहीं था, पर जब से जहानाबाद, गया, औरंगाबाद के इलाके में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अभियान तेज हुआ, इन तीनों जिलों के नक्सली छिपने के लिए भागकर चतरा के वन क्षेत्र में आ गये हैं और रातोरात चतरा पुलिस के नक्शे पर लाल लकीरों से घेर दिया गया। हां, नक्सलियों ने जब इसे अपनी शरणस्थली बनायी, तो उन्हें लगा कि आक्रोश के बीज यहां के पिछड़े लोगों में सुप्तावस्था में हैं और ये बीज फूट सकते हैं।''

हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र से कम्युनिस्ट विधायक रमेंद्र कुमार कहते हैं, ''मांडू, पतरातू, चुरचू आदि प्रखंडों में आई०पी०एफ० वाले जहां अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, वहीं एम०सी०सी० ने सिमरिया व चतरा का जंगली इलाका थाम लिया है। हजारीबाग के नक्सली गतिविधि के अड्डों पर छापामारी करने के मेरे अनुरोध पर हजारीबाग के आरक्षी अधीक्षक ने मुझसे कहा कि मैं नक्सलियों के अड्डे जानता हूं, पर मेरे पास उतना पुलिस बल नहीं कि छापे मार सकूं। जाहिर है पुलिस भी साधन के स्तर पर पंगु है। जहां तक विकास का प्रश्न है हजारीबाग, रांची और पलामू की सीमा जहां मिलती है वहां ३३००० मिलियन मीट्रिक टन

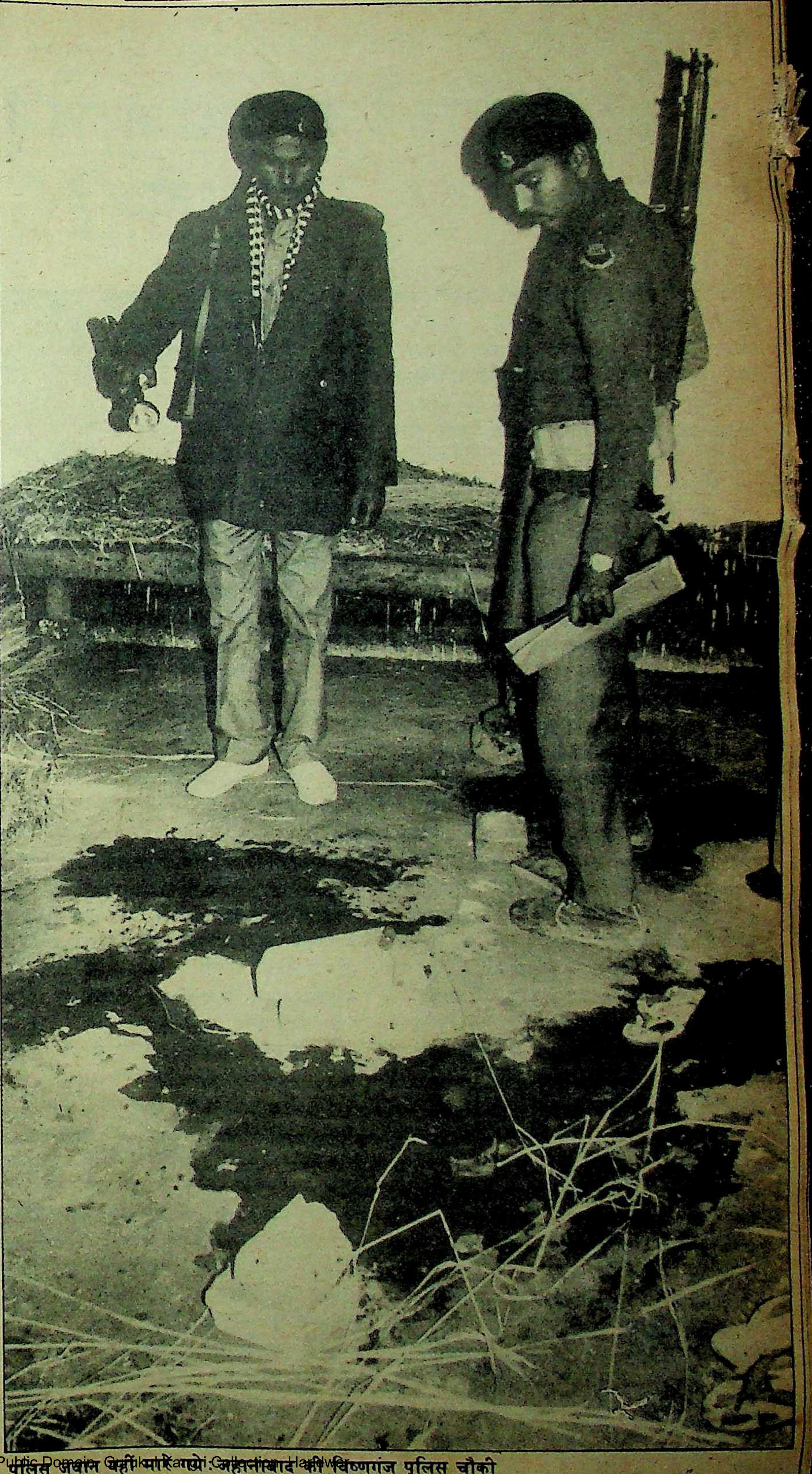

पुलिस जवान यहीं मारे गये : जहानाबाद की विष्णुगंज पुलिस चौकी

साक्षात्कार/ विधायक उमाधर सिंह (नक्सली नेता)

बिहार में जातिवादी झुकाव ने नक्सलियों को तोड़ा है

बिहार के चर्चित नक्सली नेता और हायाघाट क्षेत्र से बिहार में सी०पी०आई० (एम०एल०) के इकलौते विधायक उमाधर सिंह कानू सान्याल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (एम०एल०) की केंद्रीय समिति के प्रमुख सदस्य हैं। अभी पिछले दिनों उमाधर ने यह कहकर कि जातीय भावनाओं की विकृति ने बिहार के नक्सली संगठनों को कुंद कर दिया है, एक नयी बहस की शुरुआत की है। प्रस्तुत हैं, उमाधर से 'माया' की बातचीत के प्रमुख अंश:

माया: बिहार के नक्सली संगठनों में जातीय विकृति की बात आपने उठायी है। इसे जरा और साफ करें।

उमाधर: अरसे से भूमिगत स्तर पर बिहार में सक्रिय विभिन्न नक्सली गुट अपने 'मिशन' मे कामयाब क्यों नहीं हुए, इस पर गंभीरता से सोचने की सख्त जरूरत है। बेशक जातीय कमजोरियों ने नक्सली मुहीम को दिशाहीन बना दिया और एक बहुत बड़ी क्रांति भटक कर रह गयी। जातीय भावना का आधार प्रत्येक समाज में सामंती ढांचा रहा है। होता यह रहा कि मार्क्सवादी भाई जब अपने कार्यक्षेत्र में 'प्रैक्टिस' में उतरते हैं, तो उन्हें हर जगह बना-बनाया जातीय आधार उग्र अवस्था में छटपटाता मिल जाता है। लिहाजा, वे वर्ग संघर्ष तेज कर उस उग्र जातीय आक्रोश को खतम कर अपनी विचारधारा के अनुरूप आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाते और स्वयं भी उस जातीय भावना के बहाव में फंस जाते हैं। बिहार की शोषित धरती पर नक्सली आंदोलन की विफलता का यही प्रमुख कारण है। जाति और वर्ग संघर्ष का समानांतर चलना बेहद घातक साबित हुआ है। आज वर्ग संघर्ष तेज करने की आवश्यकता है, पर यह कठोर संघर्ष करने से नक्सली संगठन भाग रहे हैं। मार्क्सवादी भाषा में कहें, तो ये लोग 'परिस्थिति के दुमछल्ले' बन बैठे हैं।

माया: डा० विनयन, एम०सी०सी० (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर) या विनोद मिश्र गुट का लिबरेशन ग्रुप भी क्या इस स्थिति का शिकार है?

उमाधर: विनयन, को मार्क्सवादी कहना मार्क्सवाद का [illegible] है। न तो उनका जनाधार है और न ही कोई विचारधारा। हां, जब कुछ हत्याएं इन लोगों के माध्यम से हो जाती हैं, तो ये लोग सरकार और अखबार दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। विनयन महज अखबारी क्रांतिकारी हैं। अब नागभूषण पटनायक को ही लें, तो उनका अपना कोई जनाधार नहीं। आई०पी०एफ० में बस वह कठपुतली की हैसियत में हैं। सही मायने में उड़ीसा में नागभूषण के गुरु भुवनमोहन पटनायक का काफी प्रभाव है। वह हमारे साथ हैं। जहां तक एम०सी०सी० का सवाल है, यह एक घोर आतंकवादी संगठन है, जिसका उद्देश्यहीन हिंसा में विश्वास है। मार्क्सवादी विचारधारा से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हां, विनोद मिश्र का गुट बेशक जनाधार और नीतियुक्त भूमिगत मोर्चा है। विनोद मिश्र गुट से हमारे संगठन की एकता की बातें चल रही हैं। अभी विगत ८ जनवरी को हमारे संगठन, पार्टी यूनिटी और विनोद मिश्र गुट आदि ने मिलकर कलकत्ता में एक रैली भी की।

माया: आपके संगठन से संतोष राणा गुट अभी भी क्यों दरकिनार है?

उमाधर: दरअसल कई मसलों पर संतोष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या वह अमरीकी सहायता की भर्त्सना करेंगे, तो वह चुप लगा गये। अपनी मृत्यु से कुछ पूर्व उन्हीं के गुट के पुराने नक्सली नेता सत्य नारायण सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि संतोष को अमरीका से आर्थिक मदद मिलती है, पर आज तक संतोष ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की।

माया: राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख नक्सली संगठनों में एकता की कोशिश चल रही है। क्या हिंसा में आस्थावान गुप्त संगठनों को भी इसमें शरीक किया जायेगा?

उमाधर: हां एकता-वार्ता चल रही है, पर इसमें कई शर्तें भी हैं। भारत में अब तक सही मार्क्सवादी चितन का संगठन बना ही नहीं। ऐसे संगठन के लिए कितने लोग उत्सुक हैं, हम इसे पहले परख रहे हैं। देश में कई नक्सली गुट और व्यक्तिगत क्रांतिकारी भी हैं। इन सबों को एक करने पर कुछ कारगर बात हो सकती है। पहले विनोद मिश्र गुट का यह विचार था कि सिर्फ सी०पी०आई० (एम०एल०) के विभिन्न गुटों को लेकर ही सशक्त संगठन बन सकता है, पर अब वह भी यह सोचने के लिए तैयार हुआ है कि गैर सी०पी०आई (एम०एल०) को भी साथ करने में हर्ज नहीं। जहां तक गुप्त संगठनों का प्रश्न है, हथियारबंद क्रान्ति और व्यक्तिगत हत्या में फर्क होता है। हमारे कार्य में अल्पकाल के लिए 'टैक्टिस' और दीर्घकाल के लिए रणनीति बनायी जाती है। माओ ने कहा है, "टैक्टिस दस आदमी के खिलाफ एक आदमी अपनाता है और रणनीति में एक के खिलाफ दस होते हैं।" इसलिए जो गुप्त संगठन इस नीति पर चल रहे हैं, उन्हें एकता में शरीक करना अनुचित नहीं होगा।

माया: देश के विपक्षी दलों से भी आपका संगठन तालमेल की पुरजोर पहल कर रहा है। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक नीयत है?

उमाधर: व्यवस्था का बदलाव अकेले नहीं किया जा सकता। फिलहाल देश में कोई ऐसा विरोधी दल भी नहीं जिससे ऐसी उम्मीद की जाये। इसलिए हमारे महासचिव कानू सान्याल राजनीतिक दलों से भी तालमेल कर आगे के कदमों की दिशा तय करने में जुटे हैं। उनकी बातचीत लालकृष्ण आडवाणी, जनता पार्टी के नेताओं और ज्योति बसु से भी हुई है। मैंने भी जनमोर्चा और लोकदल के नेताओं को पत्र लिखकर इस आशय का अनुरोध किया है।

—विकास कुमार झा

महेंद्र सिंह भोगता

"सड़क और बिजली तथा बच्चों का स्कूल चतरा क्षेत्र के लिए सपना है। ऐसे माहौल में तो नक्सली पनपेंगे ही।"

कोयले का अकूत भंडार है। उसमें ९००० मिलियन मीट्रिक टन सेमी कोकिंग कोल के भी पाये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र को उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र कहते हैं। इस इलाके में सरकार अगर रुचि लेती, तो कम-से-कम पचास हजार लोगों को नौकरी मिलती, पर सरकार को इसमें कोई रुचि नहीं। आक्रोश और हताशा की जमीन पर तो नक्सलियों के पांव जमेंगे ही।"

बहरहाल, चतरा में २८ दिसंबर को पुलिस व एम०सी०सी० के बीच हुए खूनी टकराव को बीते अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ था कि ४ जनवरी, १९८८ को ज़हानाबाद जिले के मख्दुमपुर क्षेत्र के अतर्गत विष्णुगंज पुलिस चौकी पर अचानक तीस-चालीस की जमात में नक्सलियों का जत्था टूट पड़ा। पलक झपकते ड्यूटी पर तैनात संतरी गोपाल बहादुर को गोली मार कर ढेर कर दिया गया। फिर इससे पहले कि पुलिस के जवान संभलते हवलदार गजेंद्र सिंह, आरक्षी कालू मुरमू और शंकर यादव को भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। इस खूनी खेल में आरक्षी बबन राम बस घायल होकर ही रह गया। नक्सलियों ने उसे मृत समझ कर और गोली नहीं मारी।

पुलिस के लिए सचमुच यह खतरनाक इशारा था। नतीजतन जहानाबाद और गया का भी सीमा क्षेत्र सील कर दिया गया। विष्णुगंज पुलिस चौकी से नक्सली दो स्टेनगन, आठ राइफल और भारी मात्रा में गोलियां भी ले भागे थे। नक्सली पूरी तरह सशस्त्र हो चुके थे। हादसे के बाद पुलिस महानिदेशक एस०एन० राय सहित तमाम आला पुलिस अधिकारियों ने जहानाबाद में लंगर डाल दिया। जहानाबाद और गया के इलाके में अब तक पुलिस ही लोगों को मौत देती रही थी पर अब नक्सली उनकी भी बलि लेने लगे। जहानाबाद के जिलाधिकारी एच०एच० सिरोही कहते हैं, "हमलावरों ने बहुत सोचकर ४ जनवरी का दिन ही चुना, क्योंकि उस दिन सब जगह सोमवारी मेले की भीड़ थी। कोई सतर्क नहीं था।"

हमले की वजह : आखिर विष्णुगंज में इतनी बड़ी घटना हुई क्यों ? इसका कारण बिहार के मुख्य सचिव से लेकर पुलिस अधिकारी तक बताते हैं कि २५ दिसंबर, १९८७ को बीरा गांव में नक्सली संगठन पार्टी यूनिटी और आई०पी०एफ० के बीच किसी बात को लेकर ठन गयी। अगले दिन बीरा में छापा मारकर पुलिस ने 'पार्टी यूनिटी' के सक्रिय सदस्य बिदेश्वर मोची को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। नतीज़तन, पुलिस से इसका बदला लेने के लिए विष्णुगंज पुलिस चौकी पर हमला किया गया। यों इस तर्क में बहुत दम नहीं दीखता। बस एक ही बात झलकती है कि हथियार छीनने और एक बार फिर पुलिस को स्तब्ध कर देने के लिए नक्सलियों ने इतनी जोखिम भरी योजना को अंजाम दिया। वैसे विष्णुगंज पुलिस चौकी पर नक्सली एक बार पहले भी टूटे थे, पर कामयाबी मिली नहीं थी। विष्णुगंज के लोग बताते हैं कि पुलिस के ज़ुल्म से इलाके में काफी आक्रोश भी चल रहा था। अप्रैल, १९८७ में विष्णुगंज के एक अपराधकर्मी को जब गांववालों ने मार डाला, तो पूरे इलाके को पुलिस बेवजह कई दिनों तक परेशान करती रही।

दलेलचक-बघौरा कांड के बाद औरंगाबाद, गया और जहानाबाद को शामिल कर नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष पुलिस क्षेत्र ही बना दिया गया, पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जहानाबाद-गया में 'रेड-एलर्ट' से भी कोई फर्क नहीं।

नक्सलवाद के कारण : आखिर यह सब कब तक ? जहानाबाद के इंका विधायक असगर हुसैन कहते हैं कि इस समस्या को दूसरे ढंग से निपटना होगा। असगर का कहना है कि अब तक जब भी जहानाबाद, गया या औरंगाबाद में नक्सलियों ने हिंसा की, तो हड़बड़ाकर सरकारी अधिकारी कहने लगते कि ऐसा वाकया सामाजिक-आर्थिक कारणों की परिणति है, पर मेरा अनुभव कुछ दूसरा है। यह कहीं से भी सामाजिक-आर्थिक कारण नहीं, क्योंकि वैसा अगर होना होता, तो सबसे ज्यादा तनाव पूर्णिया और सहरसा के उन हिस्सों में होता जहां अभी भी बहुत लोगों के पास हजार एकड़ से ऊपर जमीन है। पर जहानाबाद में सौ एकड़ का जोतदार मुश्किल से मिलेगा। इसलिए ये नक्सली गतिविधियां शुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हैं। आप देखेंगे कि बिहार में सक्रिय अधिकांश नक्सली नेता पहले किसी-न-किसी राजनीतिक दल में थे। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर हार गये। ऐसे ही खारिज लोगों ने हताश होकर हिंसा का मार्ग अपनाया ताकि संसद या विधानसभा में प्रवेश मिल सके। 'मजदूर किसान संग्राम समिति' के कथित नक्सली नेता डा० विनयन शर्मा जनता पार्टी में थे। १९७७ में टिकट न मिलने पर जहानाबाद से आक्रोश में चुनाव भी लड़ गये और बुरी तरह हारे। तिलेश्वर कौशिक, जिन पर बिहार सरकार ने २५,००० का इनाम घोषित किया था, विधानसभाई चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद नक्सली नेता बन गये।"

असगर हुसैन

"बिहार में सक्रिय अधिकांश नक्सली नेता किसी-न-किसी राजनीतिक दल में थे। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर हार गये।"

क्या नक्सली इस बार भी पूरी ताकत बटोरकर छेड़ी गयी मुहिम में कारगर हो पायेंगे ? राजसत्ता पर क्या बंदूक से कब्जा हो सकेगा ? बिहार में नक्सली आंदोलन का अतीत बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। १९७० के दिनों में मुजफ्फरपुर के निकट मुसहरी में उभरी क्रांति साल लगते-लगते साफ दबा दी गयी ती। १९६९ में भोजपुर के इलाके में सुलगी नक्सली चिंगारी भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। १९७१ में भोजपुर का सहार थाना बिहार का 'नक्सलबाड़ी' बन गया था, पर वह भी ठंडा पड़ गया। आखिर इसके कौन से कारण थे और अभी मौजूदा समय में नक्सली जत्था नाकामयाब अगर होता है, तो क्यों ? इस सवाल के मंथन में खुद नक्सली जमात की रुचि नहीं है।

आपसी मतभेद : अभी हाल में नक्सली नेता और विधायक उमाधर सिंह ने यह कह कर एक बहस का मसाला दिया है कि बिहार में कार्यरत नक्सली संगठन जातीय भावनाओं के बहाव में टूट गये। पर आसार कम ही हैं कि नक्सली जमातें इस पर बहसतलब होंगी। कड़वा सच तो यह है कि भूमिगत दुनिया में बिहार के नक्सली खुद एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। डा० विनयन द्वारा संचालित 'मजदूर किसान संग्राम समिति' भी भयानक कलह की शिकार है। सी०पी०आई० (एम०एल०) की इकाई 'पार्टी यूनिटी' जहानाबाद, गया और औरंगाबाद क्षेत्र में सक्रिय थी। डा० विनयन ने जब जहानाबाद क्षेत्र में सक्रियता शुरू की, तो 'पार्टी यूनिटी' से भी सहयोग का संबंध कायम हुआ, पर बाद में डा० विनयन का कई कारणों से पार्टी यूनिटी वालों से तनाव हो गया और १५ जून, १९८७ को बाकायदा विनयन ने उससे संबंध-विच्छेद की घोषणा के साथ अपने पांच प्रमुख लोगों अरविंद, नंदलाल पंडित, शोभित, महेंद्र और मुन्ना को अपने संगठन से बर्खास्त भी कर दिया। डा० विनयन का आरोप था कि अरविंद गुट 'मजदूर किसान संग्राम समिति' के नाम पर निजी स्वार्थ में हत्याएं करता

फेर रहा है। पलटकर अरविंद गुट ने भी विनयन ी भर्त्सना की। डा० विनयन के साथ फिलहाल हानाबाद के शिकरिया पंचायत के मुखिया ंगबहादुर सिंह हैं और विष्णुदेव सिंह भी हैं। ायन पर जहां बिहार सरकार ने एक लाख रुपए ा इनाम रख छोड़ा है, वहीं जंगबहादुर और वष्णुदेव पर पचास-पचास हजार का इनाम। बहरहाल, अब विनयन और अरविंद गुट हर पल एक दूसरे के खिलाफ घात लगाये रहता है। जहानाबाद के विधायक असगर हुसैन कहते हैं, "इलाके में चर्चा है कि विनयन और अरविंद गुट के टकराव में हथियार ज्यादा अरविंद गुट को ही हाथ लगा।"

डा० विनयन

विनयन पर जहां बिहार सरकार ने एक लाख रुपए का इनाम रख छोड़ा है, वहीं जंग बहादुर और विष्णुद्वेव पर पचास-पचास हजार का इनाम।

बिहार के प्रमुख गुप्त नक्सली संगठनों में विनोद मिश्र गुट, पार्टी यूनिटी, एम०सी०सी० और कुछ क्षेत्र में के० रामचंद्रन गुट भी हाथ-पांव मार रहा है, पर तमाम नक्सली गुटों में एक दूसरे के लिए घृणित हिंसक भाव है। विनोद मिश्र गुट, एम०सी०सी० व पार्टी यूनिटी आदि के मध्य अरसे से हथियार के सहारे मतभेदों का हिसाब-किताब होता रहा है। ३ सितंबर '८७ को पार्टी यूनिटी वालों ने जब जहानाबाद जिले के अकबरपुर के बाशिंदे डा० मुश्ताक को, जो लिबरेशन ग्रुप से हमदर्दी रखते थे, मौत के घाट उतार दिया, तो बदले में लिबरेशन ग्रुप ने ५ सितंबर '८७ को माकपा गांव में से पार्टी यूनिटी के दो सक्रिय कार्यकर्ताओं को बंदूक की नोक पर उठा लिया। वे दोनों सदस्य फिर कभी लौट नहीं सके। ६ सितंबर को जब फैसला करने के लिए पार्टी यूनिटी और लिबरेशन ग्रुप ने मोर्चाबंदी की, तो एक घंटे तक गोलियां तड़तड़ाती रहीं। पुलिस के आने पर ही सब भागे। नक्सली गुटों में आपस में ऐसे हिंसक टकराव नये नहीं हैं। १९८७ के अगस्त माह में भी पटना जिले के पालीगंज क्षेत्र में लिबरेशन ग्रुप व पार्टी यूनिटी वालों के बीच घंटों तक बंदूकों से घमासान होता रहा। मुठभेड़ में लिबरेशन ग्रुप का एक सदस्य और पार्टी यूनिटी के दो कार्यकर्ता मारे गये।

लिबरेशन ग्रुप का तनाव पूर्वी चंपारण में कुछ इलाकों में चंद्रपोल रेड्डी गुट से भी काफी गहराया। रेड्डी गुट पर यह आरोप था कि टिकोनी गांव के रामचंद्र सिंह की हत्या इसी गुट ने की थी। रेड्डी गुट ने यह तर्क प्रचारित किया कि रामचंद्र सिंह सामंत-समर्थक थे जबकि दूसरी तरफ लिबरेशन ग्रुप ने बाकायदा पर्चे छापकर रेड्डी गुट की भर्त्सना की कि एक गरीब किसान की हत्या अनुचित रूप से हुई। इस क्षेत्र में लिबरेशन ग्रुप के गणेश राम और रेड्डी गुट के वीरेंद्र सिंह में अकसर टकराव की वारदातें होती रही हैं।

बिहार में सर्वाधिक हत्याएं एम०सी०सी० ने की हैं। पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस संगठन ने कुर्मियों की मदद से हरिजनों को ठिकाने लगाया, तो औरंगाबाद में यादवों की तरफ से राजपूतों की हत्या की। औरंगाबाद व गया क्षेत्र में एम०सी०सी० के कर्ताधर्ता प्रमोद मिश्र और रामाधार सिंह हैं, जिन पर बिहार सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है।

बहरहाल, आपसी कलह और सरकार की टेढ़ी नजर के बीच से शोषण की दुनिया में नक्सली कैसे अलख जगायेंगे, यह एक अहम सवाल है। इतना तो तय है कि अगर दमन से खीझे हुए लोगों को अपने नक्सली मार्गदर्शकों से भी निराशा हाथ लगी, तो इसके परिणाम बहुत दारुण और वीभत्स हो सकते हैं।

छाया : प्रभाकर, सुधांशु

—विकास कुमार झा

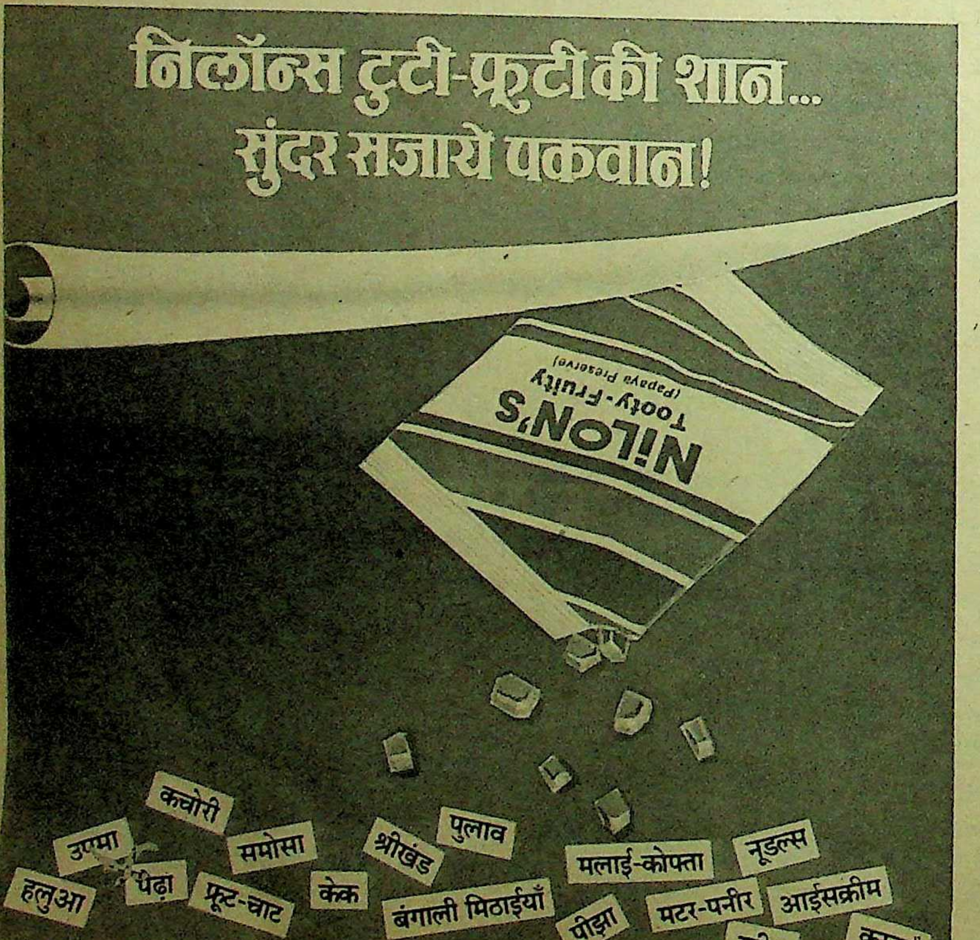

कुशल गृहिणी की खासीयत तो है ही स्वादिष्ट पकवान... लेकिन इनको आप निलॉन्स टुटी फ्रूटी से सजाएँ तो चार-चाँद लग जाएँ।

निलॉन्स टुटी फ्रूटी की विशेषताएँ...

- सबसे ज्यादा चमक
- भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाली
- अत्याधुनिक ढंग से बनी हुई
- अब घरेलू इस्तेमालके लिए १०० ग्रॅम के छोटे पॅक एवं चार आकर्षक रंगोमें उपलब्ध।

निलॉन्स टुटी-फ्रूटी केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित चिन्ह देखकर ही खरीदिये।

1021 R
FPO

NILON'S
निलॉन्स
फूड्स प्राईव्हेट लिमिटेड
निलॉन्स हाऊस, जलगाँव
(महाराष्ट्र) ४२५ ५०१.

भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाले निलॉन्स अचार के निर्माता एन-जॉय सॉफ्ट ड्रींक कॉन्सेंट्रेटके उत्पादक।

AD HOUSE 1003 HIN

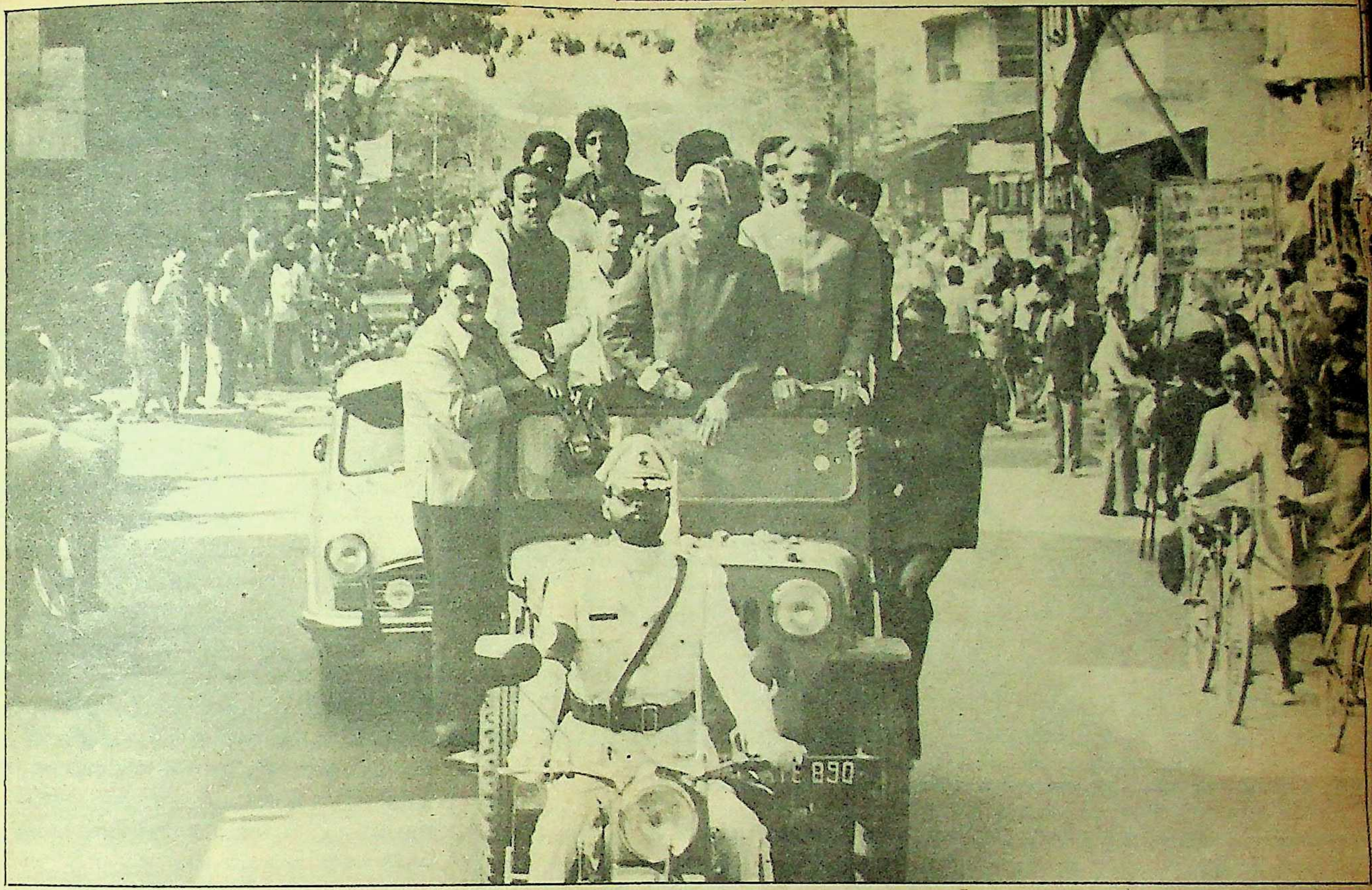

राजा का काफिला सुल्तानपुर में

राजीव के गढ़ में सिंह

अभी तक वी०पी० सिंह देश के अन्य भागों में अलख जगाते फिर रहे थे, लेकिन आठ जनवरी को उन्होंने सीधे राजीव गांधी के गढ़ पर धावा बोला। अमेठी और सुल्तानपुर क्षेत्र में जिस तरह अनूठे तोरणद्वार सजा कर उनका स्वागत किया और उनको सुनने के लिए जितनी भीड़ उमड़ी उससे इंका के खेमे में खलबली मचना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह वी०पी० सिंह के दौरों के संदर्भ में किस रणनीति पर चल रहे हैं?

१३० द्वारों में से एक

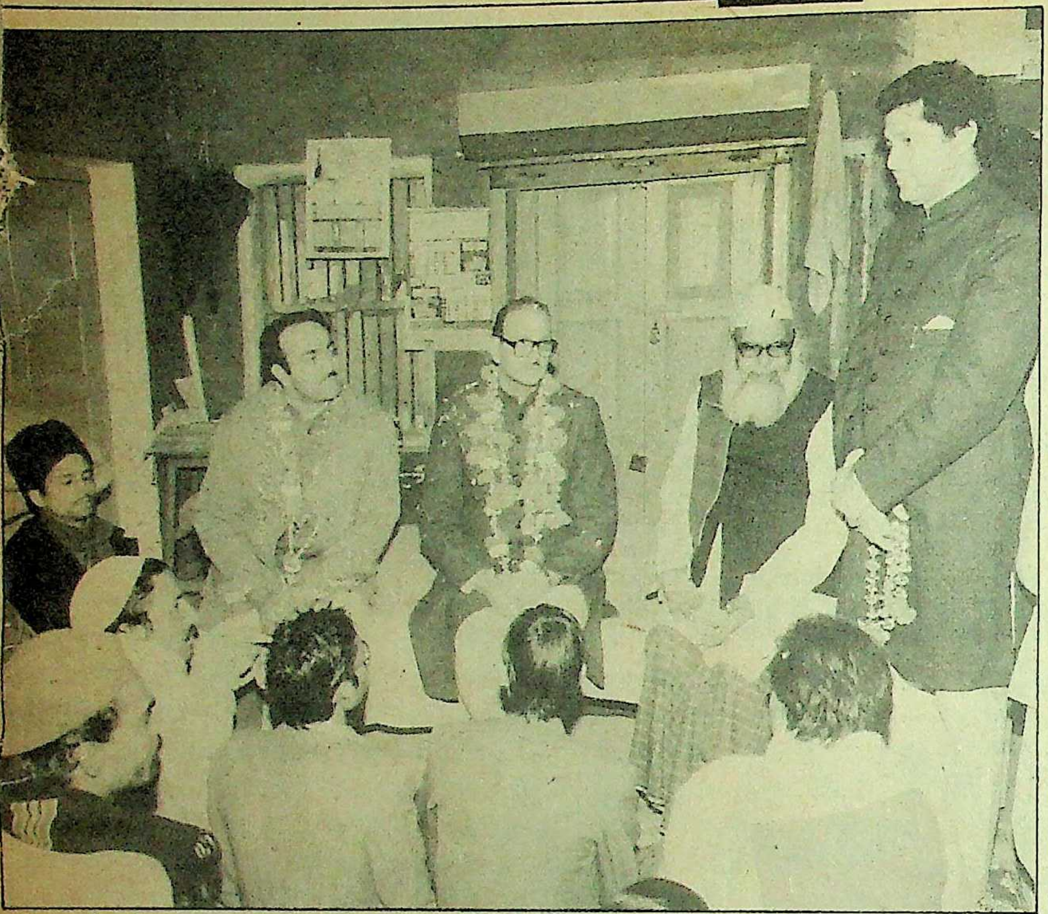

मुस्लिम वोट बैंक पर नजर : एक मस्जिद में संजय सिंह, वी०पी० सिंह और नकवी

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अगस्त, ८७ में जब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का तीन दिवसीय दौरा किया था, तो आभास हुआ था कि वहां वी०पी० सिंह और विधायक संजय सिंह का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन इसी आठ जनवरी को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सुलतानपुर यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि उनका प्रभाव राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में भी धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जनमोर्चा के गठन के बाद तीन विपक्षी दलों लोकदल-अ, जनतापार्टी, तथा कांग्रेस-स के साथ मिलाकर बने 'राष्ट्रीय मोर्चा' की सुलतानपुर जिले में आठ जनवरी को पहली जनसभा थी। वी०पी० सिंह भी कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद पहली बार सुलतानपुर पहुंचे थे। अमेठी संसदीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर दस्तक देता हुआ वी०पी० सिंह का काफिला जब इंन्हौना, मुसाफिरखाना, जगदीशपुर से गुजरा, तब उसका जोरदार स्वागत हुआ। उल्लेखनीय बात यह है कि उक्त सभी स्थान अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। मुसाफिरखाना में वी०पी० सिंह की सभा में १० हजार की भीड़ जुड़ गयी थी। इन्हौना में संजय मंच के चौधरी अजहर हुसैन ने राजा के स्वागत की तैयारियां की थीं, किंतु ऐन मौके पर उन्हें मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने लखनऊ में ही रोक लिया। इन्हौना में कांग्रेस-इ के तीन-चार कार्यकर्ताओं ने वी०पी० सिंह को काले झंडे दिखाये। वास्तव में कांग्रेसियों की योजना तो यह थी कि इन्हौना में ही राजा का काफिला रोक लिया जाये। इसी प्रयास में जनमोर्चा और कांग्रेस-इ के कार्यकर्ताओं के बीच सुबह ही मारपीट व पथराव भी हुआ। किन्तु संजय मंच का गढ़ होने के कारण जनमोर्चा यहां कांग्रेस पर भारी पड़ा। ऐसी ही स्थिति मुसाफिर खाना में भी थी। १९८० के बाद पहली बार अमेठी संसदीय क्षेत्र में विपक्षी गतिविधिया आठ जनवरी को दिखीं। राजीव गांधी की यात्रा के दौरान सारी सरकारी मशीनरी के लग जाने के बाद भी इन क्षेत्रों में इतनी भीड़ नहीं जुट पायी थी, जितनी कि सिर्फ वी०पी० सिंह के नाम पर ही जुट गयी।

अभूतपूर्व स्वागत : इसके पीछे अमेठी में विधायक संजय सिंह का बढ़ता प्रभाव है। संजय सिंह ने, जो कांग्रेस में रहने के दौरान कार्यकार्ताओं से मिलना तो दूर बात तक नहीं करते थे, जनमोर्चा में आने के बाद से अमेठी में लगातार दौरा व जनसम्पर्क किया है। उन्होंने अमेठी ही नहीं सुलतानपुर जिले के अधिकांश गांवों में जनसम्पर्क किया। यही कारण है कि संजय सिंह कांग्रेस के तमाम कट्टर कार्यकर्ताओं को जनमोर्चा में ले आये। सुलतानपुर में वी०पी० सिंह की सफल सभा कराने का श्रेय भी संजय सिंह और सुलतानपुर के पूर्व विधायक राम सिंह को जाता है। रायबरेली के अखिलेश सिंह ने भी बड़ी संख्या में जीपों व कारों में भर कर लोगों को भेजा था और यह भी संजय सिंह के इशारे पर हुआ था।

सुलतानपुर शहर में वी०पी० सिंह के स्वागत में लगभग १३० भव्य स्वागत द्वार बनाये गये थे। सुलतानपुर शहर के प्रवेश द्वार से गांधी मैदान (सभास्थल) तक की सड़क और सड़क के दोनों ओर बने मकानों की छतें भीड़ से पटी पड़ी थीं। दो किलोमीटर की यह दूरी तय करने में राजा के काफिले को ढाई घंटे का समय लगा। इस बीच कई स्थानों पर वी०पी० सिंह की आरती उतारी गयी। बैंड बाजे से स्वागत के साथ ही छतों से महिलाओं ने फूलों की वर्षा की।

राजा की सभा में अधिक भीड़ न जुट सके, यह सोच कर परिवहन निगम की सुलतानपुर जाने वाली अधिकांश बसें दो दिन पूर्व ही रद्द कर दी गयी थी। निजी बसों, टैक्सियों और जीपों को भी रोक दिया गया था। सभा में अधिक भीड़ न जुट सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने पंत स्टेडियम में सभा करने की अनुमति नहीं दी। इन सब अड़गों के बावजूद शहर के दूसरे छोर पर खेतों से लगे महात्मा गांधी इंटर कालेज के मैदान में वी०पी० सिंह को सुनने के लिए एक लाख से अधिक की भीड़ जुट गयी। गांधी मैदान पर भारी जनसमूह को देखकर जनमोर्चा के सांसद अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी आश्चर्य में पड़ गये। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाले जनपद में इतनी अधिक भीड़ की कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। अगस्त '८७ में प्रधानमंत्री की अमेठी यात्रा के दौरान जिन तीन ब्लाक-प्रमुखों भादर के राम बहादुर सिंह, मेटुआ के रामहर्ष सिंह तथा संग्रामपुर के रणधीर सिंह के कांग्रेस में आने का प्रचार किया गया था, लेकिन वी०पी० सिंह की इस सभा में इन्होंने खुलकर हिंस्सा लिया। इन लोगों ने वी०पी० सिंह की सभा में अमेठी से खासी भीड जुटाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली।

सुलतानपुर में इतनी बड़ी सभा करके जहां संजय सिंह ने राजीव गांधी को अपनी बढ़ती ताकत का अहसास कराया है, वहीं अपने पुराने विरोधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केदार नाथ सिंह के सामने चुनौती भी पेश की है। सुलतानपुर निवासी केदार नाथ सिंह अब प्रधानमंत्री की जनसभा में इतनी ही भीड़ जुटाकर इस चुनौती का जवाब दे सकते हैं।

वी०पी० सिंह ने सभा में कहा, "राजीव गांधी जब सरिस्का अभयारण्य (राजस्थान) में केबिनेट मीटिंग करने गये थे, तो वहां से दिल्ली लौटकर कोयला और शक्कर के दाम बढ़ाये गये थे। अब पिकनिक मनाने लक्ष्यद्वीप गये हैं, देखिये क्या-क्या महंगा होता है ?" उनकी बात सच निकली। उसी रात केन्द्र सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये।

वीर बहादुर की रणनीति : उधर ५ जनवरी को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के गृह जनपद गोरखपुर में वी०पी० सिंह की सभा का आयोजन करने वाले अंत तक आपस में लड़ते रहे। इसे वीर बहादुर सिंह की रणनीति का एक अंग माना जा रहा है। राजा मांडा जब पहली बार १५ जून, १९८७ को गोरखपुर गये थे, तब वीर बहादुर सिंह ने शहर में अघोषित कर्फ्यू लगाकर उनकी सभा नहीं होने दी थी। जवाब में वी०पी सिंह ने जबरन गिरफ्तारी देकर जनता की सहानुभूति प्राप्त की थी। उसी समय उन्होंने दोबारा गोरखपुर आने का वायदा किया था।

अपूर्व स्वागत: सुल्तानपुर में वी०पी० सिंह

'राष्ट्रीय मोर्चा' की पहली जनसभा वीर बहादुर सिंह को चुनौती देने के उद्देश्य से ही गोरखपुर में रखी गयी थी। वीर बहादुर सिंह ने पहले ही अपने विश्वासपात्र मार्कण्डेय चन्द्र तथा रामकरण सिंह को जनमोर्चा में शामिल करा दिया था, ताकि ये लोग जनमोर्चा में रहकर उन्हें मदद करते रहें। मुख्यमंत्री अपनी इस चाल में काफी हद तक कामयाब भी रहे।

गोरखपुर में जनमोर्चा के संयोजक नागेन्द्र नाथ सिंह, रामकरण सिंह, जनता पार्टी तथा कांग्रेस-स के कुछ लोग चाहते थे कि राष्ट्रीय मोर्चे की जनसभा में संजय मंच के विधायक वीरेन्द्र प्रताप शाही की भी मदद ली जाये। उनका मत था कि जून ८७ में जब वी०पी० सिंह गोरखपुर आये थे, तो शाही ने उनकी यात्रा को सफल बनाने में काफी मदद की थी। पर मार्कण्डेय चन्द्र ने संजय मंच की मदद लेने का विरोध किया। उनका कहना था कि शाही ने चन्द्रशेखर, वी०पी० सिंह, अजीत सिंह जैसे राष्ट्रीय नेताओं को गाली देते हुए राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों के तीन कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि मेरी इच्छा के बिना गोरखपुर में कोई सभा नहीं हो सकती। इसके जवाब में वीरेन्द्र प्रताप शाही का कहना है, "मार्कण्डेय मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं।"

बहरहाल, इस विवाद के बाद मार्कण्डेय चन्द्र ने वी०पी० सिंह के लख़नऊ स्थित निवास पर फ़ोन करके सूचना दी थी कि जनसभा के मंच पर 'संजय मंच के गुण्डों' ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कसया (देवरिया) जाकर चन्द्रशेखर, अजीत सिंह व रामधन से भी कहा कि विधायक शाही ने उन्हें गालियां देते हुए जनसभा मंच पर कब्जा कर लिया है। यह सारा ड्रामा इसलिए खेला गया, ताकि राष्ट्रीय नेतागण गोरखपुर में गये बिना ही लौट जायें। इस सब के बावजूद एक व्यक्ति जी जान से सभा को सफल बनाने में जुटा रहा और वह थे, संजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले रामपाल सिंह। चूंकि रामपाल सिंह, मार्कण्डेय चन्द्र और नागेन्द्र नाथ सिंह तीनों का ही चुनाव क्षेत्र धुरियापार है, इसलिए मार्कण्डेय जनमोर्चा में रामपाल सिंह की स्थिति कमजोर करने के लिए जी जान से जुटे थे।

दूसरी ओर वी०पी० सिंह को गोरखपुर न पहुंचने देने के लिए सभी हथकण्डे अपनाये जा रहे थे। इसी क्रम में चार जनवरी की शाम दिल्ली से लखनऊ आने वाले वायुयान की उड़ान अंतिम क्षणों में रद्द कर दी गयी। जिस ट्रेन से वी०पी सिंह दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, वह छह घंटे लेट कर दी गयी। ट्रेन को लखनऊ से १५ किलोमीटर दूर काकोरी में ही खड़ा कर दिया गया। राजा के समर्थकों ने काकोरी जाकर उनकी अगवानी की। गोरखपुर की जनसभा दो बजे होनी थी लेकिन लखनऊ में ही एक बज गया। वी०पी० सिंह जब शाम साढ़े छह बजे सभा मंच पर पहुंचे, तो लगभग ३० हजार की भीड़ उस समय भी मौजूद थी। इसके पूर्व सभा को चन्द्रशेखर, अजीत सिंह, शरत चन्द्र सिन्हा, अकबर अहमद 'डम्पी' तथा रामधन सम्बोधित कर चुके थे। जनता ने रामधन की हूटिंग की, तो उन्होंने कहा, "सभा में व्यवधान पैदा करने वाले मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के लोग हैं। अब वी०पी० सिंह नहीं आयेंगे।" इसके बाद रामधन को जनता ने भाषण नहीं करने दिया। वी०पी० सिंह ने गोरखपुर में सभामंच से आरोप लगाया, "मेरी सभा को रोकने के लिए ही वीर बहादुर ने केन्द्र सरकार से मिल कर मुझे यहां तक न पहुंचने देने के लिए सभी हथकण्डे अपनाये।

वी०पी० सिंह की गोरखपुर यात्रा के बाद अब जनमोर्चा में अन्दरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गयी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जिस गुट ने वी०पी० सिंह की गोरखपुर सभा को असफल बनाने के प्रयास किये थे, उसी गुट ने सुलतानपुर की सभा को सफल बनाने के लिए भीड़ जुटाने में काफी मदद की। इसके पीछे वीर बहादुर की यह रणनीति बतायी जाती है, कि वह अपनी कुर्सी बचाये रखना चाहते हैं। राजनीति के पंडितों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वीर बहादुर सिंह तभी तक सुरक्षित हैं, जब तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी परेशानी में हैं। सुलतानपुर में वी०पी० सिंह की सफल सभा ने निश्चित तौर पर इंका हाईकमान को परेशानी में डाल दिया है। यह बात भी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पक्ष में ही जा रही है। वीर बहादुर सिंह ने इसी के साथ अपने विरोधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केदारनाथ सिंह को भी संकट में डाल दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस-इ हाईकमान वी०पी० सिंह की चुनौती का जवाब कैसे देता है?

—निशीथ जोशी और
सुरेश द्विवेदी,

छाया: मनमोहन शर्मा,

पहाड़ का दर्द

आजादी के बाद चालीस सालों से पहाड़ी क्षेत्र के लोग टकटकी लगाये हुए हैं कि शायद किसी को क्षेत्र के विकास की बात सूझेगी, मगर आशा अब निराशा में बदल चुकी है और इसी का नतीजा है, पृथक उत्तराखंड की मांग का जोर पकड़ना। क्या समय रहते राज्य और केन्द्र की सरकारें चेतेंगी।

भारतमाताकीजय
उत्तराखण्डकीजय
उतराखण्डकीचोटीसेआजहमनेललकाराहै
यूपीसरकारकीउपेक्षासेपहाडआजतकसर्वहाराहै

आर्थिक विकास न होने से उपजी है उत्तराखंड की मांग

"पहाड़ का एक भी हितैषी ऐसा नहीं निकला, जो पर्वतीय विकास का जिम्मा ले पाता...और-तो-और सरकार ने कैसा पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया है, जिसके मंत्री के पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं।"—यह शिकायत है गढवाल के आगराखाल के बदरीराम रतूडी की। मगर कुमाऊं के झूलाघाट के शशि शंकर का सोच अलग है। उनका कहना है, "पहाड़ के कई बेटों को विकास का जिम्मा दिया गया, मगर उन्होंने अपने ही इलाकों में विकास को सीमित कर दिया। पहाड़ का कोई भी सत्ता में रहने वाला व्यक्ति यह बात मानकर नही चला कि पहाड़ एक है और उसकी विकास समस्या भी एक-सी है। किसी ने अपने को गढ़वाली समझा, तो किसी ने कुमायूंनी। किसी ने भी अपने को पूरे पहाड़ का नहीं माना। नरेंद्र सिंह भंडारी ही एक अपवाद रहे।" अब तक पर्वतीय विकास के नौ मंत्री रह चुके हैं लेकिन पहले-पहल स्व० भंडारी जो १९७१ से ७७ तक मंत्री रहे, ने ही विकास की बात सोची।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहाड़ का प्रतिनिर्धित्व कम क्यों है ? विकास के लिए धनराशि के मामले में जब हमारी तुलना हिमाचल प्रदेश से की जाती है, तब हमें प्रतिनिधित्व के मामले में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता ? आबादी और विधायकों की संख्या के आइने में जब हम इस दलील को कसते हैं, तब उनकी बात सही उतरती है। हिमाचल प्रदेश की आबादी लगभग ४३ लाख है और वहां की विधानसभा में ६८ विधायक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ४८ लाख आबादी वाले पहाड़ के आठ जिलों से सिर्फ १९ विधायक चुने जाते हैं। इसी तरह हिमालय की गोद में बसे नागालैंड, मेघालय और मणिपुर की विधानसभाओं को लिया जाये, तो क्रमशः आठ, चौदह और पन्द्रह लाख की आबादी वाले इन राज्यों में जनता के चुने हुए ६०-६० प्रतिनिधि हैं।

भेदभाव की नीति : इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ के आठ जिलों में विकास के लिए राज्य सरकार ने कोई कोरकसर नहीं उठा रखी है, लेकिन उसका लाभ पहाड़ के लोगों को कम ही मिल पाया है। इसकी वजह योजनाओं के प्रारूप और उसके उद्देश्य का लखनऊ में तय किया जाना है और जो तय करते हैं, उनकी पहाड़ के बारे में जानकारी नगण्य होती है। अगर ऐसा नहीं है, तो मैदान और पहाड़ में प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण के लिए ८१ हजार रुपए की एक-सी धनराशि क्यों आवंटित की जाती है। मैदान में सीमेंट की एक बोरी की कीमत ६५ रुपए है, जबकि पहाड़ में परिवहन लागत मिलाकर वही बोरी ढाई सौ और तीन सौ रुपए में पड़ती है। यही बात विकास की अन्य योजनाओं पर भी लागू होती है। दूसरी बात, विकास की मंथर गति और धन की लूट-खसोट ने पूरे पहाड़ में असतोष फैला रखा है। यह बात विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने स्वीकार की है। विकास के बाद भी आज पांच लाख शिक्षित बेरोजगार काम की तलाश में दर-ब-दर मारे-मारे फिर रहे हैं। यही नहीं, विकास के लिए सरकार ने जो निगम बनाये हैं, उनमें से ६ के अध्यक्ष एक ही क्षेत्र और एक ही जिले के हैं। यह तथ्य पूरे पहाड़ में सरकार की आलोचना का प्रमुख कारण बन गया है। दरअसल, पर्वतीय क्षेत्र में विकास का पूरा काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया है। युवक कांग्रेस नेता इन्दुभूषण भंडारी ने यह बात कहकर पूरे विकास कार्य पर प्रश्न चिह्न लगा दिया, "पर्वतीय क्षेत्रों में काम नहीं, अधिकारियों द्वारा कमीशनखोरी होती है।"

उत्तराखंड क्रांतिदल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी

टिहरी का दर्द : टिहरी का अपना अलग दर्द है। यह दर्द टिहरी बांध परियोजना से जुड़ा है। इस दर्द की तड़प का अहसास गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी स्थित स्वामी रामतीर्थ परिसर में चल रहे छात्र यूनियन के जलसे में हुआ। लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की सुरीली और गंभीर आवाज ने सात सौ साल के गढ़वाली इतिहास के टिहरी बांध में जल समाधि का मार्मिक चित्रण किया। इससे लोगों की आंखे भर आयीं। पर्वतीय विकास राज्यमंत्री राम अवतार दीक्षित के सामने मंच से ही यूनियन अध्यक्ष विजय सिंह पंवार कह रहे थे, "कुल ६ कमरों में २२ विषयों की कक्षाएं चलती हैं। जब कमरे बढ़ाने की बात सरकारी अफसरों से की जाती है, तब वे कहते हैं कि नये टिहरी शहर में विश्वविद्यालय का शानदार नया परिसर बन जायेगा। तब तक इंतजार कीजिए। पुस्तकालय में जो भी किताबें हैं, सब सन ५० के आस-पास की हैं। क्या नयी किताबों के लिए भी हमें नये शहर के बनने का इंतजार करना पडेगा ?"

ठसाठस भरे परिसर में छात्रो और उनके अभिभावकों की बातें सुनने के बाद कभी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन के अध्यक्ष रहे मौजूदा राज्यमंत्री दीक्षित ने यह जानकारी देकर सभी को चौंका दिया, "विश्वविद्यालय के किसी भी

जिम्मेदार अधिकारी या सरकारी अफसर ने आज तक मुझे नहीं बताया कि टिहरी परिसर में कक्षाओं के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं और छात्र पुरानी पाठ्यपुस्तकों से ही अध्ययन कर रहे हैं।'' इस सरकारी सच को उजागर करने के बाद उन्होंने यह आश्वासन देकर सबों का दिल मोह लिया, ''आप लोग विधिवत एक योजना पास कराकर मेरे पास भेजें। सरकार के पास धन की कमी नहीं है। मगर एक शर्त है कि धन के खर्च पर आप लोगों को कड़ी निगरानी रखनी होगी, तभी उसका सही इस्तेमाल और फायदा मिल सकेगा।''

बात भी सच है कि पहाड़ के लिए दो सौ करोड़ रुपये के विकास बजट का ६० फीसदी धन कड़ी निगरानी के अभाव में नौकरशाह, स्थानीय ठेकेदारों और नेताओं की चौकड़ी के हवाले हो जाता है। विकास का घोड़ा कागज पर दौड़ता है और जमीन पर उतरते ही दम तोड़ देता है।

टिहरी बांध परियोजना की अपनी अलग कहानी है, तो इससे विस्थापित होने वालों की अपनी अलग दास्तान। भागीरथी और भिलंगना नदियों को जोड़कर तैयार की जाने वाली इस परियोजना का प्रारूप १९६१-६२ में तैयार हुआ था। लेकिन, स्वीकृति दस साल बाद १९७१-७२ में मिली थी। तब इस पर १९७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। २६० मीटर ऊंचे और ४५ वर्ग किलोमीटर के दायरे में बनने वाले बांध से जब पानी छोड़ा जायेगा, तब टिहरी नगर समेत २२ गांव पूरी तरह से डूब जायेंगे और ७० गांव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। कुल ७०-७५ हजार की आबादी को विस्थापित करना पड़ेगा। बांध की वजह से अपनी जमीन, अपने घर, अपने खेत और खट्टी-मीठी यादों से उखड़ने के दर्द का इन लोगों के दिलो-दिमाग पर कितना गहरा असर है, इसकी जानकारी टिहरी नगरवासियों, के इस कथन से मिलती है, ''हमें इस बांध से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिजली जरूर मिलेगी, जो अब भी मिल रही है। इस बांध से न तो हमें सिंचाई के लिए और न ही पीने के लिए पानी मिलेगा।''

यह बात सही है कि सरकार ने विस्थापितों को बसाने के लिए चंबा ब्लाक में जमीनों का इंतजाम किया है। पहाड़ पर पहला नियोजित शहर बनाया जा रहा है। लेकिन, यह भी सच है कि नये शहर और नये गांवों से पुराने शहर और पुराने गांवों की यादों की भरपाई नहीं हो सकेगी—भले ही भरपाई के रूप में विस्थापितों को कितनी ही रकम क्यों न दे दी जाये ? अलबत्ता इस पीढ़ी के बाद नयी पीढ़ी के लिए सब कुछ सपना-सा होगा। यहां के इंका विधायक लोकेंद्रदत्त सकलानी का मानना है, ''मैदान की तरक्की के लिए हमारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। इस कुर्बानी की महत्ता के आगे मुआवजे की रकम बौनी पड़ गयी है। जिस हिसाब से बांध की कीमत बढ़ी है, उसी हिसाब से पुनर्वास का भी खर्च बढ़ना चाहिए। उन लोगों को बांध से पैदा होने वाली बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, जिन्हें अपने घरबार से उखड़ना पड़ रहा है।''

छाया: मनमोहन शर्मा, राजेन्द्र कुमार

—अशोक रजनीकर

राजनीति के विभिन्न रंग

पहाड़ की राजनीति मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बंटी हुई है। पहली राजनीति इंका से प्रभावित है, तो दूसरे पर पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग हावी है। तीसरी राजनीति अपेक्षाकृत कमजोर है और जनमोर्चा तथा विपक्ष में बंटी हुई है। गढ़वाल और कुमायूं दोनों ही मण्डलों में १९ विधायक और चार लोकसभा के सदस्य हैं। गढ़वाल क्षेत्र में १० विधायक हैं जिनमें शिवानंद नौटियाल (कर्णप्रयाग) को छोड़कर सभी इंका के हैं। दो संसद सदस्य—ब्रह्मदत्त (केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री) और चंद्र मोहन सिंह नेगी पिछले महीने तक कांग्रेस के लोकसभाई सदस्य थे। अब नेगी जनमोर्चा में चले गये हैं। विधायक पुष्कर सिंह रौथाण (पौड़ी) और सुरेंद्र सिंह नेगी (लैंसडाउन) को जनमोर्चा का साथ देने के लिए इंका की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया है, जबकि रोथाण का कहना है, ''मेरी निष्ठा अब भी पूरी तरह से राजीव गांधी के नेतृत्व में है और मैं शुरू से ही कांग्रेस का सदस्य रहा हूं।'' इसी तरह पौड़ी के १५ ब्लाक प्रमुखों में से १३ जनमोर्चा के साथ चले गये हैं। देवप्रयाग के इंका विधायक सूर्यवीर सिंह सजवाण भी संदेह के दायरे में हैं। पता चला है कि वह कभी भी जनमोर्चा या उत्तराखंड क्रांतिदल में जा सकते हैं। शेष ६ इंका विधायकों के बारे में वहां के इंका कार्यकर्ताओं का कहना है, ''कोई नारायणदत्त का आदमी है, तो कोई ब्रह्मदत्त का, तो किसी को चंद्रमोहन सिंह नेगी और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस का टिकट दिलवाया था।'' जब पूछा गया कि कोई कांग्रेस या राजीव गांधी का भी आदमी है, तो कार्यकर्ता अगली-बगली झांकने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरह नेताओं की व्यक्तिगत निष्ठा में फंसे हुए हैं।

यही बात कुमायूं क्षेत्र पर भी लागू है। यहां भी इंका के विधायक या तो नारायणदत्त के आदमी हैं या फिर कृष्णचंद पंत और सांसद हरीश रावत के आदमी हैं। किसी भी कार्यकर्ता के मुंह से यह सुनने को तरस गये कि वह कांग्रेस का आदमी है और उसकी निष्ठा दल के नेता के प्रति है। बहरसूरत, इंका के निराशा के इस क्षण में अगर पहाड़ पर आशा की कोई किरण है, तो वह है युवा कांग्रेस। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के अनेक कालेजों की छात्र यूनियनों पर उनका कब्जा है। तेज तर्रार नौजवान होने के नाते उनकी धाक है। लेकिन, कब तक ? अगर उन्हें संगठन में मौका नहीं दिया गया, अगले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया और विकास के बावजूद उनके बीच से बेरोजगारी दूर नहीं की गयी, तो वे कभी भी अलग उत्तराखंड राज्य का झंडा उठा सकते हैं या फिर अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए विपक्ष का सहारा ले सकते हैं।

अगर पहाड़ पर आशा की कोई किरण है, तो वह है युवा कांग्रेस। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के अनेक कालेजों की छात्र यूनियनों पर उनका कब्जा है। तेजतर्रार होने के नाते उनकी धाक भी है। लेकिन, कब तक ?

पृथक उत्तराखंड की मांग करने वाले उत्तराखंड क्रांतिदल के प्रबल प्रभाव के बावजूद कुमायूं मंडल में इंका के लिए संतोष करने का एक कारण मौजूद है। अभी यहां के कांग्रेसजनों में वी०पी० सिंह की तरफ झुकाव पैदा नहीं हुआ है। फिर भी, पिथौरागढ़ के नौजवान इंका नेता और उत्तर प्रदेश इंका अल्पसंख्यक सेल के संयुक्त सचिव इकबाल बख्श ने गत मई में जिला कांग्रेस सम्मेलन में राज्यमंत्री राम अवतार दीक्षित और सांसद हरीश रावत की मौजूदगी में वी०पी० सिंह के समर्थन में नारे लगाये थे। अब वह त्यागपत्र देकर क्रांतिदल में शामिल हो गये हैं। गढ़वाल मंडल के देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, सतपुतली और पौड़ी आदि स्थानों का दौरा कर वी०पी० सिंह ने जनमोर्चा के लिए पहाड़ पर प्रारंभिक हवा तो बहा दी है। अभी से यह बताना मुश्किल है कि कुमायूं क्षेत्र में दौरा होने पर वी०पी० सिंह का यहां के इंका क्षेत्र में कितना असर पड़ेगा।

कुमायूं क्षेत्र के तीनों जनपद—पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल—के दो लोकसभाई सदस्य कांग्रेस के हैं। एक हरीश रावत, दूसरे नारायणदत्त के खासुलखास सत्येंद्र गुड़िया। कुल नौ विधायकों में तीन विपक्ष के साथ हैं। उत्तराखंड क्रांतिदल के अध्यक्ष काशीसिंह ऐरी डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुने गये हैं। जनता पार्टी के टिकट पर के०एन० पांडे निर्वाचित हुए हैं और हाल ही में संजय मंच के अकबर अहमद 'डम्पी' ने उपचुनाव में नारायणदत्त तिवारी के किले काशीपुर को ढहा दिया है। शेष ६ इंकाई विधायक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे दत्त, पंत और रावत में किसके साथ जायें और किसके साथ न जायें। वी०पी० सिंह और उत्तराखंड क्रांतिदल के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस को बचाने के लिए मार्च में श्रीनगर (गढ़वाल) में कार्यकर्ताओं का एक वृहत सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए पर्वतीय विकास राज्यमंत्री दीक्षित पहल कर रहे हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लाने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में गत २८ दिसंबर को लखनऊ में पर्वतीय विकास दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। कुल मिलाकर कोशिश इस बात की हो रही है कि मंत्री-नेताओं में बंटी कांग्रेसी निष्ठा को संगठन और पहाड़ के विकास की तरफ मोड़ा जाये। देखना है कि इस प्रयास से भी पहाड़ को अपना बेटा मिल पाता है या नहीं या फिर पहाड़ अपने राजनीतिक बेटे की तलाश अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में करता है।

—अशोक रजनीकर

भारतीय जनता पार्टी
द्वितीय महाधिवेशन
दि. 25,26,27 दिसम्बर-87

अंतर्कलह : भाजपा अधिवेशन

भाजपा

उदारपंथी बनाम कट्टरपंथी

राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का हाल में चुनाव हुआ, जिसमें ललित किशोर चतुर्वेदी चुने गये। लेकिन इनके निर्वाचन से पार्टी में कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच चल रही तनातनी सतह पर आ गयी। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भाजपा और आर०एस०एस० के अंतसंघर्ष से राजस्थान शाखा कैसे मुक्त हो सकती है? लेकिन अध्यक्ष के चुनाव के बाद दो धड़ों में जो द्वंद्व बढ़ा है, क्या उससे पार्टी की शक्ति अक्षुण्ण रह सकेगी?

भारतीय जनता पार्टी हिन्दू सापेक्ष पार्टी रहे या धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में विकसित हो, यह एक ऐसा मुद्दा है जो इस 'कैडर-बेस' दल के उदार कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर परेशान कर रहा है। राजस्थान में इस परेशानी ने हाल में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दौरान उग्र रूप धारण कर लिया। प्रदेश भाजपा ने निर्णय किया था कि उदयपुर में २५ से २७ दिसंबर '८७ तक आयोजित उनके द्वितीय महाधिवेशन से पूर्व वह प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। परम्परा से ये चुनाव निर्विरोध होते रहे हैं, पर इस बार उदारवादियों ने अपनी ओर से पहला नामांकन पत्र भरकर कट्टरवादियों को शक्ति-परीक्षण के लिए मजबूर कर दिया।

इस दल में जनतांत्रिकता का आभास देने के लिए वांछित प्रक्रियाएं दिखायी जाती हैं, पर होता वही है जो आला नेता चाहते हैं। बहरहाल, पहला नामांकन पत्र युवाओं की उपेक्षा के रोष का इजहार करते हुए ईश्वर सिंह चौधरी ने दाखिल किया। चौधरी के प्रस्तावकों में दल द्वारा तय किये गये प्रदेश के २८ जिलों में आठ का समर्थन हासिल था। ईश्वर सिंह इसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं।

१५ दिसंबर को दाखिल इस नामांकन पत्र को २० दिसंबर '८७ तक वापस लेना था। उधर दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी को जयपुर केवल इसलिए भेजा गया था कि वह शक्ति-परीक्षण को टालें। पर उनकी उपस्थिति में ही प्रदेश भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा और विधायक दल के उपनेता ललित किशोर चतुर्वेदी ने चौधरी के नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद अपने नामांकन पेश कर दिये। इन तीनों के अलावा भाजपा विधायक हरिकुमार औदिच्य और पूर्व भाजपा विधायक गुरुशरण छाबड़ा भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में आ गये।

प्रस्तावकों की सूची से स्पष्ट हो रहा था कि ललित किशोर चतुर्वेदी को १९ जिलों के उन पदाधिकारियों का समर्थन हासिल था जो पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में आस्था रखते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष एवं विधायक भंवरलाल शर्मा को इस मामले में विधायक दल एवं विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत के परोक्ष समर्थन के साथ-साथ कुल दो विधायकों का प्रस्तावक के रूप में समर्थन हासिल था। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के समर्थकों की सूची देखने के बाद दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी ने विधायक दल के नेता भैरोंसिह शेखावत, उपनेता ललित किशोर चतुर्वेदी, दल के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा,. महामंत्री जगदीश प्रसाद माथुर से बंद कमरों में विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श का असर केवल भारतीय युवा जनता मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौधरी और गुरुशरण छाबड़ा पर पड़ा, जिन्होंने नाम वापस लेने की तिथि २० दिसंबर '८७ से पूर्व १९ दिसंबर को अपना नाम ललित किशोर चतुर्वेदी के पक्ष में वापस ले लिया। इन लोगों के ललित किशोर चतुर्वेदी के पक्ष में जाते ही शक्ति-परीक्षण की बाजी दल के कट्टरपंथियों के हाथ लग गयी।

ऐसा लगा कि दल के कट्टरपंथी, उदारवादी नेता भैरोंसिह शेखावत को शिकस्त देने के लिए युवाओं की हर बात से सहमत हो गये। हालांकि भैरोंसिह शेखावत दल के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का समर्थन यह जानते हुए कर रहे थे कि शर्मा आर०एस०एस० में दीक्षित विधायक हैं। उन्हें आभास था कि राजनीति की व्यावहारिकता ने शर्मा को कट्टरपन से मुक्ति दिला दी है। यही बात कट्टरपंथियों की नजर में शर्मा का अवगुण बन गयी। उनके अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के विरुद्ध जनता सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सतीश चन्द्र अग्रवाल व कृष्ण कुमार गोयल, प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा के साथ-साथ विधायक चम्पालाल बांठिया, कालीचरण सर्राफ, हरीश कुमावत, नाथू सिंह, गणेश लाल बैरागी, प्रभुलाल एवं पूर्व विधायक जीतमल जैन व शिवनारायण शर्मा भी ललित किशोर चतुर्वेदी के पक्ष में शामिल हो गये।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी ने शक्ति-परीक्षण टालने के लिए प्रदेश महामंत्री जगदीश प्रसाद माथुर के साथ दिल्ली के नेताओं को आगाह किया। १९ दिसंबर की शाम भाजपा के केंद्रीय महामंत्री और राजस्थान में चुनाव-पर्यवेक्षक केदारनाथ साहनी ने ललित किशोर चतुर्वेदी को फोन पर नवंबर के आखिरी

सप्ताह में राजस्थान के संदर्भ में लिये गये फैसले की याद दिलायी। जानकार सूत्रों के अनुसार उक्त बैठक में भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, केदारनाथ साहनी के अलावा राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भैरोंसिंह शेखावत ने भाग लिया था और फैसला किया था कि भंवरलाल शर्मा को पुन: अध्यक्ष निर्वाचन किया जाना चाहिए। ललित किशोर चतुर्वेदी ने साहनी को फैसले पर विचार करने का आश्वासन दिया, पर उसके बाद वह नामांकन पत्र वापस लेने के दिन यानी २० दिसंबर '८७ को उस वक्त तक लुप्त रहे, जब तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता था। नतीजा यह हुआ कि दल की एकता बनाये रखने के लिए उदारवादियों को शक्ति-परीक्षण टालने के लिए नामांकस पत्र वापस लेने पड़े। परिणामस्वरूप ललित किशोर चतुर्वेदी भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बन गये।

मतभेद: राष्ट्रीय मुद्दों के अतिरिक्त भाजपा विधायक दल के नेता भैरोंसिंह शेखावत की कार्यप्रणाली से भी कट्टरपंथियों का मतभेद है। मसलन शेखावत अपने उदार दृष्टिकोण के कारण सत्ताधारी दल से सीधी टकराहट की जगह बातचीत में विश्वास रखते हैं, जबकि कट्टरपंथी संघर्ष में ही समस्याओं का समाधान देखते हैं। पिछले विधानसभा सत्रों में राजस्थान में चर्चित नीमरोट कांड और वकील सुरेश गुप्ता-हत्याकांड पर दल के नेता की हैसियत से शेखावत ने मुख्यमंत्री जोशी पर सीधे आरोप लगाने की अनुमति विधायकों को नहीं दी। यह अलग बात है कि विधायक उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए बोले। उस वक्त बात यहां तक बढ़ी थी कि शेखावत ने दल के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में बड़े नेताओं के समझाने-बुझाने से उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस लिया था।

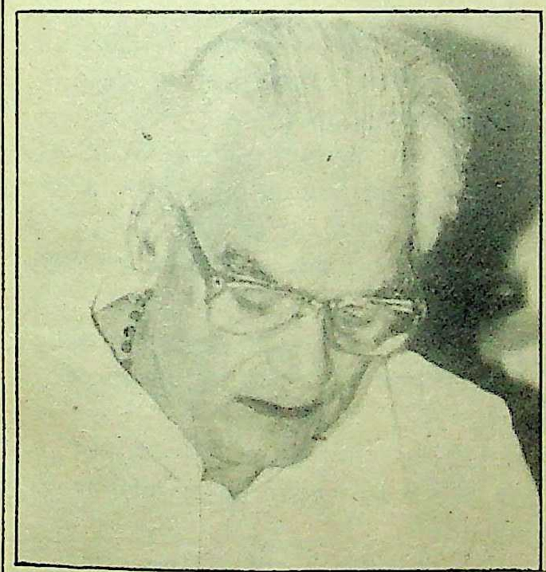

उदारवाद के समर्थक: भैरोंसिंह शेखावत

शेखावत दरअसल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पर्याय बन गये हैं। उनकी शख्सीयत को चुनौती देना दल के लोगों की क्षमता से बाहर है। सिर्फ इसी कुंठा से दल के कट्टरपंथी नेताओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र अग्रवाल और कृष्णकुमार गोयल का समर्थन हासिल हुआ है। अग्रवाल जयपुर के जौहरी बाजार निर्वाचन से १९५७, १९६२ और १९६७ में विधायक रहे हैं। सातवीं लोकसभा के लिए जयपुर से निर्वाचित हुए थे और वह जनता सरकार में राज्य वित्तमंत्री के पद पर रहे थे। जनसंघ में रहने के कारण इन्हें प्रदेशाध्यक्ष का पद भी हासिल था। आठवीं लोकसभा के लिए १९८४ में जब चुनाव हुए, तो सतीश चंद्र अग्रवाल कांग्रेस-इ के ऐसे उम्मीदवार से पराजित हुए, जिसका जयपुर में कोई आधार नहीं था। इसी तरह कोटा शहर में कृष्ण कुमार गोयल कांग्रेस के उम्मीदवार से शिकस्त खा गये। इसके विपरीत शेखावत ३८ विधायकों के साथ विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे और दल तथा विपक्ष के नेता बन गये। इस दौरान ललित किशोर चतुर्वेदी कोटा से निर्वाचित होकर विधायक दल के उपनेता तो बन गये, लेकिन जल्द ही पराजित कांग्रेसी उम्मीदवार की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और विधानसभा के सदस्य की हैसियत से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। वर्तमान में चतुर्वेदी विधानसभा के सदस्य तो हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण वह विधानसभा में मतदान एवं विवाद में हिस्सा लेने से वंचित हैं।

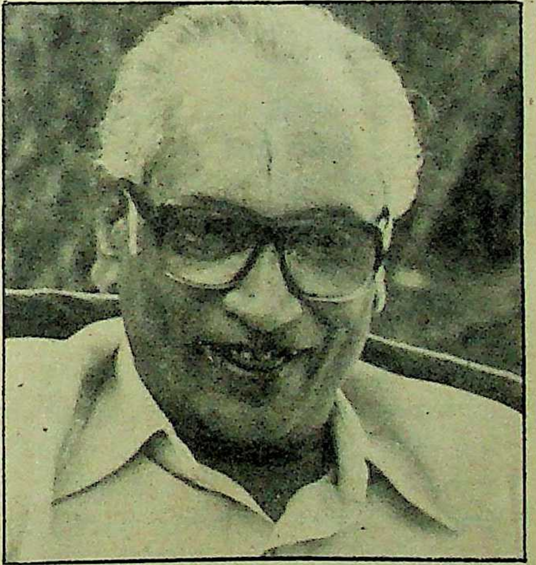

कट्टरपंथियों को समर्थन: सतीश चंद्र अग्रवाल

राजपूत समर्थन: तीन लाख के लगभग सदस्यतावाली भारतीय जनता पार्टी की १४ जून, १९८० को राजस्थान में स्थापना हुई थी और तदर्थ संयोजक जगदीश प्रसाद माथुर के बाद पहले निर्वाचित अध्यक्ष वर्तमान विधायक हरिशंकर भाभड़ा बने थे। १९८१ से लेकर १९८५ तक भाभड़ा प्रांतीय अध्यक्ष रहे, जिनसे शेखावत की नहीं पटी। भाजपा के स्थायी किस्म के महामंत्री जगदीश प्रसाद माथुर ने तो जयपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में हार के लिए शेखावत पर आरोप लगाया था कि जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह राठौड़ को उनके सामने खड़ा करवाने में शेखावत का ही हाथ था। दरअसल शेखावत को राजपूतों का पक्षधर माना जाता है। यह सच भी है। प्रथम आम चुनाव (१९५२) में जनसंघ को राजस्थान विधानसभा में आठ स्थान प्राप्त हुए थे, जिसकी एकमात्र वजह जागीरदारी-समर्थन था। यही समर्थन द्वितीय विधानसभा में समाप्त हुआ, तो जनसंघ सदस्यों की संख्या घट कर छह रह गयी। पर जब भैरोंसिंह शेखावत को जनसंघ का प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया, तो तृतीय एव चतुर्थ आम चुनावों में इसे क्रमश: १[illegible] व २२ स्थान प्राप्त हुए। शेखावत के प्रयासों से ही चतुर्थ आम चुनाव में जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी में चुनाव समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जनसंघ को अपेक्षाकृत अधिक सफलता हासिल हुई थी। इसे संयोग ही कहा जायेगा कि तब के स्वतंत्र पार्टी के कर्ता-धर्ता कल्याण सिंह कालवी जनता पार्टी में शेखावत के विशेष कृपापात्र रहे। शेखावत ने उन्हें जनता सरकार के दौर में उपचुनाव लड़ाकर अपने मंत्रिमंडल में लिया। जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ, तो शेखावत का हिन्दू मन उन्हें भाजपा की ओर खींच ले गया, जबकि कल्याण सिंह कालवी अपनी जोड़-तोड़ से जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बन बैठे। बहरहाल, पिछले आम चुनाव में कालवी और शेखावत दो अलग-अलग दलों का संचालन कर रहे थे। पर शेखावत जहां कालवी के हितों को ध्यान में रख रहे थे, वहीं कालवी, शेखावत के इशारे को समझते थे। इन दोनों राजपूत नेताओं में पहली बार तनाव 'सती धर्म रक्षा समिति' के आंदोलन को लेकर उत्पन्न हुआ है। पर ललित किशोर चतुर्वेदी समर्थकों का मानना है कि शेखावत आज भी राजपूत-हितों के सामने दलीय हित गौण कर देते हैं।

बहरहाल ललित किशोर चतुर्वेदी के प्रांतीय अध्यक्ष बन जाने के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का तीन दिवसीय द्वितीय महाधिवेशन २५ दिसंबर '८७ को उदयपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के दौरान पारित राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र व राज्य सरकार को आर्थिक व राजनीतिक मोर्चों पर असफल एवं निकम्मी सिद्ध करते हुए मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से संबंधित सुरेश गुप्ता तथा नीमरोट कांड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। यह उल्लेख एक प्रकार से उदारपंथियों के नेता भैरोंसिंह शेखावत पर सीधा हमला था। यही वजह रही कि तीन दिन के इस सम्मेलन में ज्यादातर समय भैरोंसिंह शेखावत मंच से परे रहे।

भले ही आज उदारपंथी 'केडर-बेस' दल की विशेषता के तहत यह मानने से मुकर जायें कि शेखावत उदयपुर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। पर सच यह है कि शेखावत ने सम्मेलन के आयोजकों से कह दिया था कि उनके नहीं आने से भी काम चल सकता है। शेखावत सिर्फ इसलिए सम्मेलन में शामिल हुए क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी ने स्पष्ट कर दिया था कि भैरोंसिंह शेखावत सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, तो वह भी नहीं आयेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के बाद कट्टरपंथी बैचेन हुए और शेखावत को उदयपुर सम्मेलन में शामिल होने के लिए टेलीफोन खटखटाये। शेखावत इसके बाद अधिवेशन के पहले दिन रात्रि को उदयपुर पहुंचे।

साक्षात्कार/ललित किशोर चतुर्वेदी,

मैं भी आर०एस० एस० के लोगों में एक हूं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रहे ललित किशोर चतुर्वेदी जनसंघ के संगठन मंत्री रहे हैं। वह पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर कोटा से चुन कर विधानसभा में पहुंचे थे। जनता पार्टी के विभाजन के बाद भाजपा में आये। इस बार भाजपा के अध्यक्ष बनने से पहले शेखावत से पाली जिले में विधायक खंगार सिंह की नियुक्ति को लेकर विवाद में आये। इस जिले के तेरह मंडलों में आठ ने भाजपा कार्यकर्ता अमृत परमार को अपना अध्यक्ष बना रखा है, जबकि पाली की विधायक कुमारी पुष्पा जैन ने विधायक खंगार सिंह को अध्यक्ष घोषित कर रखा है। ललित-किशोर चतुर्वेदी एक सांस में दो बात कहते हैं, यानी एक ओर वह शेखावत को अपना नेता मानते हैं, तो दूसरी ओर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और उनके द्वारा समर्पित उम्मीदवार का विरोध करना अपना जनतांत्रिक अधिकार मानते हैं। प्रस्तुत हैं, बातचीत के कुछ अंश:

माया: आपके अध्यक्ष बनने को लेकर कई कथाएं हैं, सच क्या है?

चतुर्वेदी: अध्यक्ष को लेकर अखबारों में जो विभिन्न प्रकार की खबरें हैं, वे सच नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की हेरारकी में मुझसे सीनियर जितने बन्धु हैं, वे सभी अध्यक्ष बन गये। इसलिए सामान्यरूप से सारे नक्शे में जो हेरारकी है, उसमें नाम मेरा ही आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन के नाते आया हूं। १९६६ में जब मैंने जनसंघ से रिजाइन किया, उस समय जो मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि भई राजनीति में बड़े पुल्स और प्रेशर होते हैं, आपको मानसिक रूप से बहुत वेदना होगी। उस समय जनसंघ का कोई ऐसा स्वरूप नहीं था, जिसे देख कर लगता कि कभी मैं एम०एल०ए० बन जाऊंगा या कभी हमारी सरकार भी होगी। ऐसा लगता था कि एक पीढ़ी को तो घुटने रगड़-रगड़ के निकाल देना है। कोई नतीजा निकलेगा, तो अगली पीढ़ी को कुछ हासिल होगा। इसी मिशन (भावना) के साथ सरकारी नौकरी छोड़ कर मैं राजनीति में आया था। तब से आज तक पहले जनसंघ फिर जनता पार्टी और आज भाजपा में काम कर रहा हूं। कभी इच्छा नहीं हुई कि अध्यक्ष बनें या मंत्री। पर लगातार कार्यकर्ताओं की इच्छा और हेरारकी में मेरा नाम होने से मैं अध्यक्ष के लिए खड़ा हो गया।

माया: केंद्रीय नेतृत्व ने आपको चुनाव से हटने के लिए कहा था क्या?

चतुर्वेदी: ऐसा बिलकुल नहीं है। केंद्रीय नेताओं का यह एक मत था कि यूनेनिमस (निर्विरोध) चुनाव हो जाये। हमारे यहां आंतरिक जनतंत्र है। इंका मुख्यमंत्रियों की तरह नेता नहीं थोपे जाते। अखबारों में छपी सारी बातें असत्य हैं।

माया: इसके पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी क्या इस तरह से नामांकन पत्र भरे गये थे?

चतुर्वेदी: हमारे संविधान में हाल में संशोधन हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर एक टाइम टेबल बना है, जिसका पालन अब हम लोग कर रहे हैं। इसी टाइम टेबल के अनुसार हम लोगों ने इस बार प्रदेश संगठन के चुनावों में हिस्सा लिया।

माया: कहा जाता है कि निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा को पुनः अध्यक्ष बनाने का फैसला केंद्रीय नेताओं ने एक माह पहले ही अपनी बैठक में कर लिया था।

चतुर्वेदी: ऐसी कोई बैठंक नहीं हुई। न यह हमारी जानकारी में है और न ही इस संबंध में किसी से कुछ कहा गया।

माया: शेखावत की कार्यशैली से आपका कोई विरोध है?

चतुर्वेदी: शेखावत हमारे नेता हैं। और यह जो कहा जा रहा है कि वह केवल राजपूत नेता ही हैं, गलत है। देखिए १९५२ के पहले चुनाव में जो जीत कर आये थे, वे सभी राजपूत थे। लेकिन जागीरदारी प्रथा पर भारतीय जनसंघ का एक स्टैंड होने के कारण उन्हें छोड़ कर जाना पड़ा। केवल दो ही लोग भैरोंसिह शेखावत और झाला (महारावल) लक्ष्मण सिंह) साहब ही हमारे साथ रहे। फिर शेखावत भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्गों के नेता हैं। उन्हें किसी एक वर्ग का नेता मानना उचित नहीं है।

माया: शेखावत ने उदयपुर सम्मेलन में आने से इनकार क्यों किया?

चतुर्वेदी: नहीं-नहीं बिलकुल नहीं किया। मैं स्वयं उनसे बातचीत करने गया था और मैंने पूछा था आप किस प्लेन से पधार रहे हैं। चूंकि बीच में एक समाचार आया था कि चंद्रास्वामी से उनका अहमदाबाद में कोई कार्यक्रम तय हुआ है। मुझे उन्होंने बताया कि चंद्रास्वामी ने मुझे वहां बुलाया है और वहां से सीधा मैं कार से आ जाऊंगा। किन्तु किसी कारण से वह वहां नहीं जा पाये, फिर प्लेन लेट हो गया इसलिए देर से पहुंचे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कार्यक्रम में नहीं आऊंगा।

माया: अडवाणीजी ने नहीं कहा कि यदि शेखावत नहीं आयेंगे, तो मैं भी नहीं आऊंगा?

चतुर्वेदी: अडवाणीजी का कार्यक्रम तो बहुत पहले तय हो गया था और वह तो वहा आ गये थे। ऐसे में यह तो कहने का सवाल ही नही उठता।

माया: शेखावत को मनाने जैसी बात नहीं हुई?

चतुर्वेदी: मैं कह रहा हूं न कि सिर्फ चंद्रास्वामी के कार्यक्रम की बात थी, उसके बाद कार से सीधे उदयपुर आने का कार्यक्रम तय था। मनाने का सवाल तो नाराजगी के बाद में आयेगा न?

माया: चंद्रास्वामी से शेखावत साहब का क्या ताल्लुक है?

चतुर्वेदी: चंद्रास्वामी हमारे और एस०के० जैन (और जे०के० जैन) के साथ आये थे। कोई कार्यक्रम अहमदाबाद में तय था, जिसका मुझे पता नहीं। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, उसमें से सीधा मैं सम्मेलन में आऊंगा।

माया: शेखावत ने पिछले दिनों नेतापद से इस्तीफा क्यों दिया था?

चतुर्वेदी: यह जानकारी हमें अखबारों से मिली। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वी पर्सनली एप्रोच्ड हिम (हम खुद उनके पास गये)। बातचीत की, तो बोले इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है।

माया: नीमरोट कांड उनकी इच्छा के बगैर विधानसभा में उठाये जाने पर वह नाराज थे?

चतुर्वेदी: नाराजगी की कोई बात ही नहीं। वह तो खुद इस समाचार से आश्चर्यचकित थे।

माया: राजस्थान में आर०एस०एस० और भाजपा के क्या संबंध हैं?

चतुर्वेदी: आर०एस०एस० के बहुत से लोग भाजपा में हैं। मैं भी उनमें एक हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल में जाने के लिए स्वतंत्र है। हां, विचारों का साम्य होने के कारण सामान्य आकर्षण उसका पहले जनसंघ में था और अब बीजेपी में है।

माया: क्या आप 'हिन्दू राष्ट्र ही राष्ट्रहित' की मान्यता के हैं?

चतुर्वेदी: नहीं! भाजपा ने पंच निष्ठाओं को माना है। हम कार्यकर्ता की हैसियत से उन्हें ही प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।

—ओम सैनी

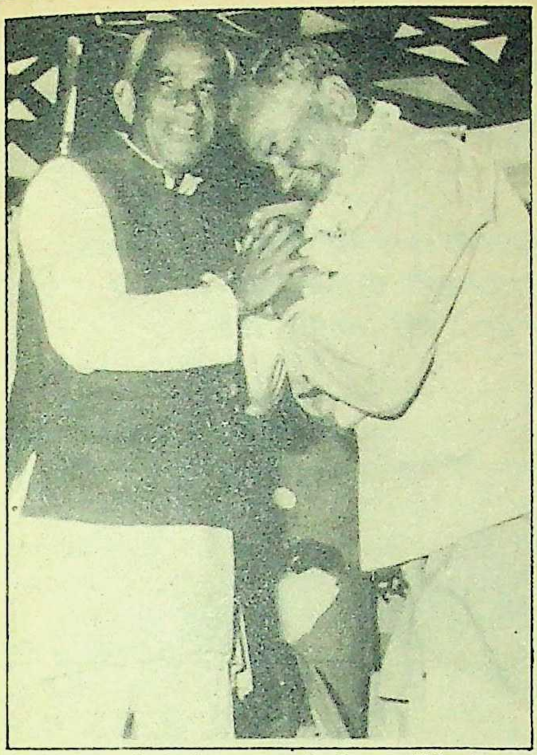

निवर्तमान और वर्तमान : शर्मा और चतुर्वेदी (माला पहने हुए)

निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा नये अध्यक्ष को कार्यभार देकर मंच से दूर कार्यकर्ताओं में विचरते रहे। अपनी नाराजी का अहसास उन्होंने उस वक्त कराया, जब नये अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। इस भाषण के दौरान शर्मा मंच से उठे और अदृश्य हो गये। सम्मेलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी ने हालांकि हर मौके पर शेखावत के नेतृत्व में अपनी आस्था जतायी, पर शेखावत की खिन्नता बरकरार रही। आज जबकि प्रदेश भाजपा बाहरी तौर पर एक नजर आती है, आंतरिक रूप से उसमें सैद्धांतिक एवं कार्यशैली को लेकर दो धड़े हो गये हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति की हाल की बैठक में 'हिन्दु राष्ट्र ही राष्ट्रहित' जैसी बात राजनीतिक प्रस्ताव में जोड़ने की बात सामने आयी, तो भैरोंसिंह शेखावत ने अटलजी, सिकन्दर बख्त और आरिफ बेग के साथ इसका विरोध किया। एर्नाकुलम (केरल) से मिली खबरों के मुताबिक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमाता विजयाराजे सिंधिया विंश्व हिन्दू परिषद की ट्रस्टी के रूप में और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे आर०एस०एस० समर्थक भाजपा की हिन्दू संगठन के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं। अब जबकि प्रदेश भाजपा पर कट्टरपंथी आर०एस०एस० समर्थकों का कब्जा है, भैरोंसिंह शेखावत की कार्यशैली के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी।

शेखावत ने सती प्रकरण में सती-प्रथा का विरोध किया है। इस विरोध के परिणामस्वरूप राजपूतों का धर्मांध तबका उनके विरुद्ध है, वहीं कट्टरपंथियों की केंद्रीय नेता श्रीमती सिंधिया ने भी सती होने को ग़लत नहीं माना है। कुल मिलाकर भाजपा में विकसित हो रहे उदारवाद के खिलाफ कट्टरपंथियों ने चौतरफा हमला किया है। राजस्थान में इस हमले में उन्हें आर०एस०एस० का सक्रिय सहयोग हासिल है। आर०एस०एस० में प्रचारक रहे ललित किशोर चतुर्वेदी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो प्रचारक ही उनकी कार्यसमिति और समर्थकों में प्रमुख हैं। उधर शेखावत आर०एस०एस० की दीक्षा से वंचित होने के साथ-साथ प्रजातांत्रिक शक्तियों की एकता के हामी हैं, जिसके संबंध में वर्तमान प्रदेश-नेतृत्व भिन्न धारणा रखता है। कट्टरपंथियों के लिए समस्या केवल भैरोंसिंह शेखावत के व्यक्तित्व की है जो पहले आम चुनाव से लेकर आज तक इस तरह विकसित हुआ कि उसके बगैर भाजपा अथवा जनसंघ की कल्पना राजस्थान में नहीं की जा सकती।

छाया : गोपाल संगर

—ओम सैनी

भाजपा की राष्ट्रस्तरीय रणनीति

शेर को उसकी मांद में घुसकर ललकारना निश्चय ही आक्रामक मुद्रा की निशानी है, किंतु दूसरी ओर अविवेक अथवा हताशा की भी द्योतक है। विशेषकर तब, जब शक्ति संदिग्ध हो। हो।

सुदूर एर्नाकुलम (केरल) में भाजपा की हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिन की बैठक के बारे में यह बात पूर्णतया खरी उतरती है। हां, भाजपा जहां दक्षिण में कम्युनिस्टों को उनके अपने ही गढ़ में चुनौती देकर अपनी साख जमाने के कारण मूंछों पर ताव दे रही है, वहीं कम्युनिस्ट इसे भाजपा द्वारा खुद को अखिल भारतीय पार्टी सिद्ध करने का एक हताशापूर्ण प्रयास मान रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव एम० फारूकी के अनुसार, "भाजपा ने वामपंथी राज्य केरल में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर वहां सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने की बात सोची है, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी।" दोनों ही दावों में तथ्य और अतिशयोक्ति का मिश्रण है।

बैठक में पारित प्रस्तावों द्वारा कांग्रेसी कुशासन के विरुद्ध युद्ध जारी रखने की घोषणा तो है ही, साथ ही साम्यवादियों के कथित दोगलेपन और राष्ट्रविरोधी रवैये के विरुद्ध भी जंग का खुला एलान भी निहित है। बैठक से पहले बांटी गयी २८ पेजी रपट ने साम्यवादियों के प्रति पार्टी की भावी रणनीति की दिशा स्पष्ट कर दी है। जाहिर है कि भाजपा वामपंथियों की दिल्ली रैली द्वारा किये गये शक्ति प्रदर्शन को बिना अपने अस्तित्व पर आंच आये नजरअंदाज नहीं कर सकती।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अस्तित्व और महत्व का प्रश्न भाजपा के लिए विशेष मायने रखता है। यही उसकी तात्कालिक और दूरगामी रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य भी है। कुछ पर्यवेक्षक भाजपा की दूर के राज्यों में राज कर रहे वामपंथी दलों से उलझने को केवल अपनी ताकत जाया करना मान रहे हैं, किंतु जिस गंभीरता से कम्युनिस्टों को दिल्ली में लिया जाने लगा है, वह भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया है। और-तो-और एक समय वी०पी० सिंह भी उन्हें अपना स्वाभाविक साथी कहने के लिए बाध्य हुए थे। उन्हें केंद्र सरकार तथा कम्युनिस्ट तालमेल से राजनीतिक व्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने की दीर्घकालीन चिंता है, तो दूसरी ओर गैर-कम्युनिस्ट व कम्युनिस्ट तालमेल की स्थिति में स्वयं के राजनीतिक अछूत बनने की आशंका। अतः कम्युनिस्टों के खिलाफ मोर्चा खोल अपने को बराबर का दर्जा दिलाने की कोशिश के अतिरिक्त भाजपा के पास फिलहाल कोई और चारा नहीं।

भाजपा की यह रणनीति एक तीर से दो शिकार की अपेक्षा रखती है। वामपंथियों को दी चुनौतियों द्वारा वह वामपंथी पार्टियों को इस बात से आगाह कर रही है कि जिन क्षेत्रों में वामपंथी ताकतों का असर नगण्य है, वहां कोई भी संयुक्त मोर्चा भाजपा की उपेक्षा करते हुए कामयाब नहीं हो सकता। भाजपा को अकेले चलने में कोई एतराज नहीं, किंतु यह कतई बर्दाश्त नहीं कि गैर वामपंथी विपक्ष कम्युनिस्टों से हाथ मिलाये। भाजपा की वर्तमान प्रसन्नता और उत्साह का प्रमुख कारण पार्टी महासचिव कृष्ण लाल शर्मा के अनुसार यही है, "भाजपा को अलग-थलग करने के सारे प्रयास विफल हो गये। इसके विपरीत कम्युनिस्ट स्वयं अलग-थलग हो गये हैं। उनके 'स्वाभाविक सहयोगी' विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उन्हें छोड़ अन्य दलों के साथ गठबंधन करना बेहतर समझा है।"

कम्युनिस्टों के विरुद्ध नये मोर्चे से कांग्रेस विरोधी अभियान धीमा पड़ जायेगा, ऐसा आलोचकों का विश्वास है। शायद यही भाजपा चाहती भी है। विपक्षी एकता कांग्रेस का विकल्प नहीं बना सकती, ऐसा उनका विश्वास है। उसके लिए जरूरी है उचित माहौल। कदाचित इसी माहौल को बनाने के लिए भाजपा ने १७ से २४ जनवरी तक के देशव्यापी 'जेल भरो' आंदोलन का निश्चय किया है। इसके तहत १० लाख भाजपाई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे।

विपक्ष को भाजपा से हिन्दूवादी पार्टी होने के कारण परहेज है। पार्टी धर्म निरपेक्षता का चोला धारण करे अथवा कट्टरवादी बनी रहे इस द्वंद्व का पार्टी ने इस बैठक में समाधान खोजना शायद लाभदायक नहीं समझा। फैसले को मध्यावधि चुनाव अथवा आम चुनाव के फौरी लाभ को मद्देनजर रख फ़िलहाल लटकाये रखना एक कारगर रणनीति का अहम अंग प्रतीत होता है। आगे क्या होगा, यह तो समय ही बतायेगा?

—रंजना [illegible]

अज्ञात बीमारी की चपेट में बस्तर

अभी मध्यप्रदेश सरकार गैसपीड़ितों के आंसू पोंछ भी नहीं पायी थी कि बस्तर के एक आदिवासी गांव गोंड़बिनापाल में विगत अप्रैल से दिसंबर तक तकरीबन २८ मौतें एक अज्ञात बीमारी के तहत हो गयीं। जब राजीव गांधी आदिवासियों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो मोतीलाल वोरा क्यों उदासीन हैं?

असहाय: रामबाई और शिवप्रसाद

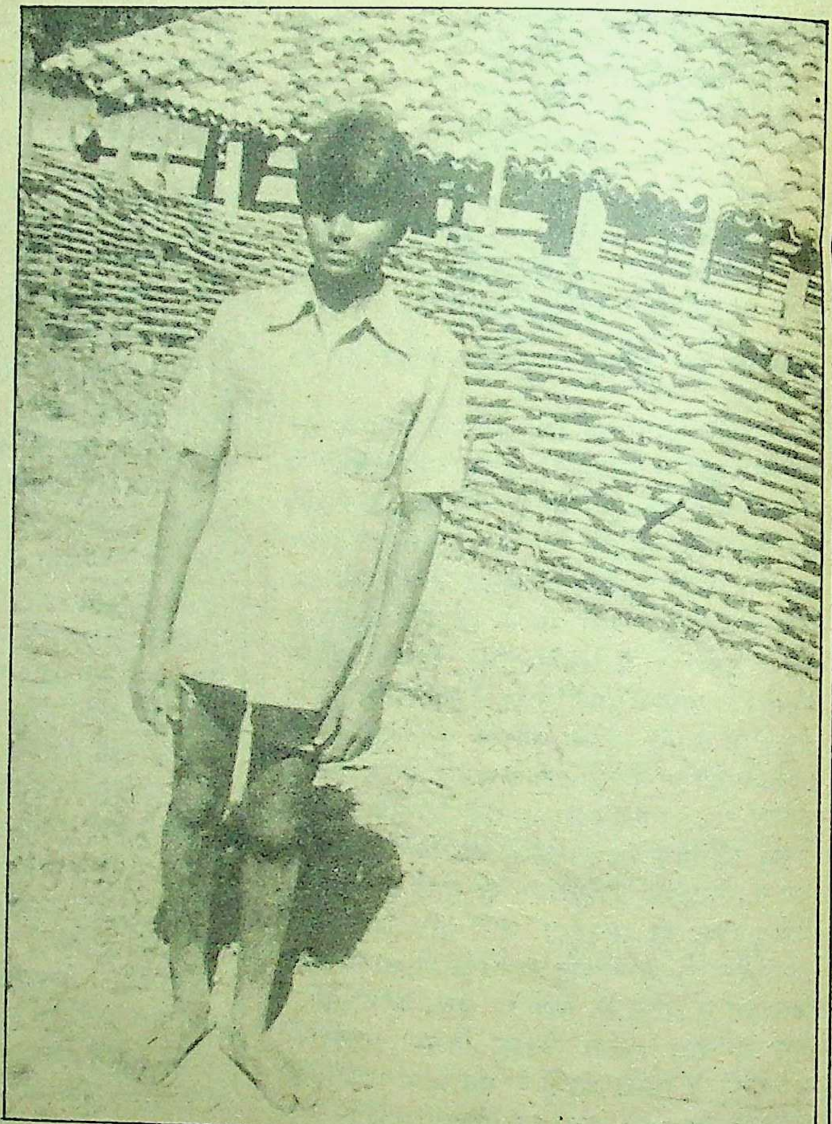

पूरे परिवार का भार: जंगलू

चौदह दिसंबर को बस्तर के गोंड़बिनापाल गांव में तीन साल के बच्चे की अज्ञात जानलेवा बीमारी से मौत के साथ ही, इस आदिवासी गांव में अज्ञात बीमारी से मरनेवालों की संख्या २८ तक पहुंच गयी। करीब चार किमी० की परिधि में फैले गोंड़बिनापाल गांव में रहस्यमय बीमारी का पहला शिकार अंजोरी राम गोंड का एक साल का नन्हा बेटा रामचरण हुआ था। रामचरण की मौत २६ अप्रैल को गांव के ओझा के घर पर हुई थी और तब से लेकर आज तक दो तिहाई से अधिक लोगों की मौत झाड़-फूंक करने वाले ओझाओं, बैगाओं और गुनियों के यहां हुई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अट्ठाईस लोगों की असमय मौत के बाद भी अभी तक गोंड़बिनापाल के लोगों ने अपने गांव में किसी सरकारी डाक्टर का चेहरा नहीं देखा है। इस रोग से मुक्ति के लिए वे आज भी बैगाओं और ओझाओं पर आश्रित हैं।

काला साया: २६ अप्रैल को जब यकबंयक आदिवासी बालक रामचरण की मृत्यु हुई थी, तब न तो अंजोरी गोंड और न ही गोंड़बिनापाल के लोग यह जान पाये थे कि अज्ञात बीमारी किसी मनहूस चील की तरह गांव पर अपने डैने पसार चुकी है। रामचरण की मौत के ऐन दो दिन बाद उजियारिन बाई की मौत से तो जैसे मौतों का अटूट सिलसिला ही प्रारंभ हो गया। इस सिलसिले ने अबोध बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को नहीं बख्शा।

जंगलू की उम्र फिलहाल केवल पंद्रह वर्ष है और उसके किशोर कधों पर दो भाइयों व एक बहन के लालन-पालन का दायित्व आ पड़ा है। १७ जून को जंगलू के पिता लक्खू गोंड की और कुछ दिनों बाद उसकी मां कोलीबाई की रहस्यमयी बीमारी से मृत्यु हो गयी। जंगलू का छोटा भाई शिवप्रसाद गांव की प्राथमिक शाला में दूसरी कक्षा में पढ़ता है और छोटी बहन रामबत्ती पहली कक्षा में। हत्प्रभ और अनाथ जंगलू अभी यह तय नहीं कर सका है कि शिवप्रसाद और रामबाई को आगे पढ़ाये या

अर्थाभाव में उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दे। इन चारों बच्चों को थोड़ा बहुत सहारा अपनी नानी कुंडदीबाई का है। वृद्धावस्था के कारण अशक्त कुंडदीबाई नातिन-नातियों के दु:ख से बेतरह दु:खी है, लेकिन बीमारी ने उसके पति लहतू गोंड को छीनकर उसके दु:ख को दूना कर दिया है।

घसियाराम का आधा परिवार अब तक इस बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ३५ वर्षीय घसियाराम खुद इस बीमारी का शिकार होने से बाल-बाल बचा है। उसके पिता सकरू गोंड और बड़े भाई दानू की बीमारी से मौत हो चुकी है। मां, भाभी और उनके दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब अकेले घसियाराम पर है। बूढ़े फागूराम का तो सारा परिवार ही होम हो चुका है। देश की आजादी के अगस्त माह में फागूराम का एक वर्ष का पोता सोहन बीमारी की चपेट में आकर चल बसा। दो दिन बाद १५ अगस्त को पत्नी सोमेबाई की अज्ञात बीमारी से मौत हो गयी। दु:खी-जर्जर फागूराम के भाग्य में अभी और दु:ख बदा था। यही वजह है कि २४ अगस्त को उसके बेटे रैसिंह की भी मौतं हो गयी और इस प्रकार बीमारी की मार से बूढ़े फागूराम की बुढ़ापे की लाठी भी टूट गयी।

बदनसीबों और दुखियारों के इस गांव पर मौत का काला साया सात माह से मंडरा रहा है, लेकिन उनकी सुध लेनेवाला कोई नहीं है। बीमारी के कारण अजरू गोंड अब गांव में निपट अकेला है। उसकी पत्नी दुकरीबाई और दोनों बेटे—राकेश और जोहन—अज्ञात बीमारी से ग्रसित होकर दम तोड़ चुके हैं। अब तक मरे २८ लोगों में से महरूराम, मानसू, सकरूराम, अनुसुइयाबाई, दयावती, सुशीला और रैसिंह की ही मृत्यु अपने घरों में हुई है, अन्यथा शेष सभी ने ओझाओं, गुनियों और बैगाओं के घर दम तोड़ा है।

सरकारी सलूक : गोंड़बिनापाल गांव के घरों में मौत अभी भी दस्तक दे रही है, लेकिन इस भयावह दस्तक के सात माह बाद भी आज तक सरकारी हाकिमों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। २० सूत्री कार्यक्रम में अपनी उपलब्धियों के लिए लंबे चौड़े इश्तहार देकर अपने गाल बजाने वाली सरकार को आदिवासियों की मर्मांतक पीड़ा को गुनने और उनकी गुहार को सुनने की फुर्सत नहीं है। गोंड़बिनापाल से मात्र छह किलोमीटर दूर स्थित अंतागढ़ के शासकीय चिकित्सालय के सरकारी अमले को आदिवासियों की मौतों से कोई लेना-देना नहीं है जबकि गोंड़बिनापाल में अज्ञात बीमारी से मौतों की सूचना विकास खंड अधिकारी, अंतागढ़ को मई में ही मिल गयी थी। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या चिकित्सक तो गांव नहीं पहुंचे, मगर विकास खंड अधिकारी महोदय का आगमन दो जुलाई को गांव में अवश्य हुआ। वापस लौटकर अगले ही दिन तीन जुलाई को उन्होंने प्रधानाध्यापक को शासकीय पत्र लिखा और उन्हें डांट पिलायी। उन्होंने प्रधानाध्यापक को यह निर्देश दिया कि प्राथमिक शाला के समीप लगे चांपाकल (हैंडपंप) के सामने गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी का वह स्वयं प्रबंध करें और अज्ञात बीमारी की रोकथाम न होने पर उन्हें सूचित करें। इसे विडंबना और सरकारी तंत्र के रवैये की बानगी कहा जा सकता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी (वि०खं० अधिकारी) ने बीमारी से ग्रस्त एक समूचे गांव के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी एक प्रधानाध्यापक के कंधों पर डालकर छुट्टी पा ली। जुलाई में ही तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी भी गोंड़बिनापाल आये, मगर उनका आना भी महज खानापूरी साबित हुआ। गांव के बीमार बाशिंदों की सुध लेने की उनकी नीयत न थी।

असहाय : किस्सा यहीं खतम नहीं होता। गोंड़बिनापाल में आदिवासियों की मौत ने सरकार की निष्क्रियता और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को भी उजागर किया। संविद शासन में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके बद्रीनाथ बघेल इस क्षेत्र से कांग्रेस-इ के टिकट पर निर्वाचित विधायक हैं। श्री बघेल ने अपने कर्तव्य के निर्वाह में कोई कोताही नहीं की। आदिवासियों की मौतों की खबर सुनकर गोंड़बिनापाल पहुंचने वाले वह पहले जनप्रतिनिधि हैं। गांव से लौटकर उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बस्तर के कलेक्टर और कमिश्नर को तत्काल पत्र लिखा था। ३० जुलाई को लिखा यह पत्र कछुए की रफ्तार से भी चला होगा, तो यकीनन अब तक गंतव्य तक पहुंच गया होगा, मगर जब मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और स्वास्थ्य मंत्री बालेंदु शुक्ल ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक को पत्रोत्तर देना तो दूर, पावती भेजना तक जरूरी नहीं समझा, तो फिर कलेक्टर और कमिश्नर से क्या उम्मीद की जाये? नारायणपुर में माटी की मड़ैया में बद्रीनाथ बघेल की जब 'माया' से चर्चा हुई, तो वह आदिवासियों की उपेक्षा को लेकर अत्यंत उत्तेजित थे। उन्होंने कहा, "आदिवासियों की मौतों को सरकार कभी गंभीरता से नहीं लेती। एक आदिवासी विधायक द्वारा लिखे पत्र का जवाब भला कलेक्टर क्यों देने लगा? उसे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे जैसा एक आदिवासी विधायक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है?" बातों से लगा कि बघेल को आदिवासियों की पीड़ा गहरे सालती है, तो क्या यह सच है कि जनप्रतिनिधि का सीधा औरं सज्जन होना उसकी निधि नहीं, दुर्बलता व दुर्गुण है?

गोंड़बिनापाल में अज्ञात बीमारी के कारण मरने वाले आदिवासियों की सूची

क्रम	मृतक का नाम	पिता का नाम	आयु	मृत्यु-तिथि	स्थान
१.	रामचरण	अंजोरीराम गोंड	१ वर्ष	२९.०४.८७	ओझा के घर
२.	उजियारिन बाई	डूडो गोंड	१६ वर्ष	०२.०५.८७	ओझा के घर
३.	महरूराम	सुकालू गोंड	७० वर्ष	०९.०५.८७	अपने घर
४.	दुकरी बाई	अजरू गोंड (पति)	२० वर्ष	१४.०५.८७	ओझा के घर
५.	मानसू	रघुनाथ गोंड	२० वर्ष	१६.०५.८७	अपने घर
६.	बज्जू	मंगतूराम गोंड	५५ वर्ष	१७.०५.८७	ओझा के घर
७.	सोमनाथ	जगनू गोंड	६ वर्ष	०१.०६.८७	अस्पताल में
८.	सकरूराम	दुकारू राम	७५ वर्ष	०४.०६.८७	अपने घर
९.	बुई बाई	लाठी गोंड (पति)	८० वर्ष	१५.०६.८७	ओझा के घर
१०.	अनिताबाई	दारसू गोंड	१ वर्ष	१५.०६.८७	ओझा के घर
११.	लक्खू गोंड	सुखद गोंड	३५ वर्ष	१७.०६.८७	ओझा के घर
१२.	कोली बाई	लक्खू गोंड (पति)	३० वर्ष	२६.०६.८७	ओझा के घर
१३.	लुहते गोंड	लाठी गोंड	५५ वर्ष	३०.०६.८७	ओझा के घर
१४.	राकेश	अजरूराम	१ वर्ष	२०.०७.८७	ओझा के घर
१५.	जोहन	अजरूराम		२४.०७.८७	ओझा के घर
१६.	धनायबाई	बुई गोंड (पति)	६० वर्ष	२७.०७.८७	ओझा के घर
१७.	कमीन बाई	सम्पत गोंड	१ वर्ष	२७.०७.८७	ओझा के घर
१८.	अनुसुइयाबाई	दारसूराम	२ वर्ष	०५.०८.८७	अपने घर
१९.	सोहन	रैसिंह गोंड	१ वर्ष	१३.०८.८७	ओझा के घर
२०.	सोमेबाई	फागूराम (पति)	६० वर्ष	१५.०८.८७	ओझा के घर
२१.	दयावती	कचोरी गोंड	११/२ वर्ष	१५.०८.८७	अपने घर
२२.	सुशीला	घासीराम	२ वर्ष	२३.०८.८७	अपने घर
२३.	रैसिंह गोंड	फागूसिंह गोंड	३५ वर्ष	२४.०८.८७	अपने घर
२४.	दानू गोंड	सकरू गोंड	४५ वर्ष	२८.०८.८७	ओझा के घर
२५.	केजोबाई	मंगलराम (पति)	२२ वर्ष	०६.१०.८७	ओझा के घर
२६.	बुलाबाई	रघुनाथ (पति)	६० वर्ष	१७.१०.८७	ओझा के घर
२७.	मोहन	गजेरसिंह गोंड.	१ वर्ष	२९.१०.८७	ओझा के घर
२८.	रामनाथ		३ वर्ष	१४.१२.८७	अस्पताल में

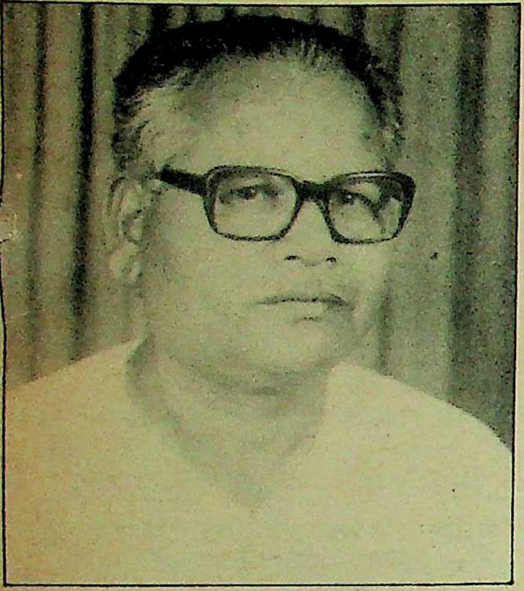

गुहार अनसुनी : विधायक बद्रीनाथ बघेल

गोंड़बिनापाल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पशुधन और डेयरी मंत्री श्रीमती गंगा ठाकुर पोटाई का गांव है। अप्रैल '८७ के बाद वह कई बार अपने गांव का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन पड़ोसी गांव में आदिवासी भाई-बहनों की मौत की ओर ध्यान देना उन्हें गवारा नहीं हुआ। आदिवासियों के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता से मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा बखूबी वाकिफ हैं। इसे बस्तर का सौभाग्य कहें या विडंबना कि वोरा स्वयं बस्तर के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसके बाद भी लगता नहीं कि देश के सबसे बड़े जिले बस्तर का कोई माई-बाप है, जो उसकी सुनता हो।

५ जनवरी को 'माया' ने जब इस बारे में मुख्यमंत्री वोरा से संपर्क किया, तो उन्हें इस तथ्य की जानकारी ही नहीं थी कि बस्तर में गोंड़बिनापाल नामक किसी गांव में बीमारी से २८ मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने खूनी पेचिश से ३०० के करीब मौतों को गलत बताया और कहा कि बस्तर प्रवास के दरम्यां वह कई गांवों में गये थे। पेचिश से ३६ से अधिक मौतें नहीं हुई हैं और मृतकों के संबंधियों को पांच-पांच हजार रुपए देने का उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही क्रैश-योजना के तहत बस्तर में डाक्टरों की नियुक्ति भी की जा रही है। बातचीत से स्पष्ट है कि विधायक का पत्र या तो मुख्यमंत्री सचिवालय की फाइलों में दबा है या मुख्यमंत्री उसे पढ़कर भूल गये।

गोंड़बिनापाल में अब तक २८ मौतों के अलावा बस्तर में खूनी पेचिश से तीन सौ से अधिक आदिवासी मर चुके हैं। मौतों के बावजूद बस्तर आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। खूनी पेचिश से मृत आदिवासियों के परिवारों को पांच-पांच हजार रुपए देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल में, जो धांधली हो रही है, पता नहीं उसकी खबर मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को है भी या नहीं ? खबर न होना और खबर होने पर भी हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना— दोनों ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी विफलता की परिचायक हैं।

—बस्तर से, सुधीर सक्सेना और भरत अग्रवाल

शाही शादी का विवाद

ग्वालियर में सजग नागरिक मंच की सक्रियता और नेपथ्य के घटनाक्रम से लगता है कि शाही शादी का विवाद अभी थमा नहीं है। अमूमन, बिटिया की शादी करके लोगबाग चैन की सांस लेते हैं, किंतु केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया अपनी इकलौती बेटी चित्रांगदा राजे की शादी करके मुसीबत और विवाद में फंस गये हैं। इन दिनों शाही शादी को लेकर उनके राजतीतिक विरोधियों ने उनकी नींद हराम कर रखी है और यह इसी तीखे अभियान का परिणाम है कि विवाह को निजी और पारिवारिक मसला माननेवाले सिंधिया को अपनी चुप्पी तोड़कर बयान देने को बाध्य होना पड़ा है।

माधवराव सिंधिया पर शाही शादी में सरकारी मशीनरी और मन्नूराजे ट्रस्ट की संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। सिंधिया को आरोपों से बेधनेवालों में विपक्षी नेताओं के साथ-साथ उनके ही दल के कुछ प्रभावशाली लोग और स्वयं उनकी मां विजयराजे सिंधिया शामिल हैं। उनकी मां ने तो यहां तक कह डाला कि करने को तो उन्होंने भी बेटियों और बेटे की शादी की थी, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग व अपव्यय के बल पर वैभव का ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, जैसा उनके बेटे ने उनकी पोती की शादी में किया।

रोन से निर्वाचित इंका विधायक रमाशंकर सिंह की गिनती शुरू से सिंधिया के मुखर विरोधियों में होती है और यह सच है कि वह दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ग्वालियर में डेरा डालकर खासे सक्रिय रहे। रमाशंकर के रेसकोर्स रोड स्थित बंगले ने ११ दिसंबर के आसपास किसी प्रेस के दफ्तर का रूप ले रखा था, जहां स्थानीय और बहिरागत संवाददाताओं को 'ब्रीफ' करने का काम सुनियोजित अभियान के रूप में चला और इस अभियान की बागडोर रमाशंकर ने सीधे अपने हाथों में रखी। बीते बरसों में सिंधिया विरोधी अभियानों में अर्जुनगुट के सिपहसालार भगवान सिंह यादव अत्यंत सक्रिय रहे हैं, किंतु इस बार लगता है कि यह दायित्व पूरी तौर पर युवा तुर्क नेता रमाशंकर सिंह को सौंप रखा था।

इसमें संशय नहीं कि सिंधिया ने विवाह को अचर्चित रखने के लिए अपनी ओर से काफी जतन किया किंतु शुरू में प्रेस को आयोजन से परे रखने का उनका पांसा उलटा पड़ गया और उपेक्षा से क्षुब्ध पत्रकारों ने सिंधिया विरोधी नेताओं द्वारा थमाये गये आरोपों के पुलिंदों का जी भर के इस्तेमाल किया। मजे की बात यह है कि कम्युनिस्ट नेता कामरेड होमी दाजी ने शाही शादी को लेकर जो आरोप लगाये; वे तकरीबन वही आरोप थे, जिनका सिंधिया विरोधी कांग्रेस खेमे द्वारा बांटे गये खर्रों में उल्लेख था।

शाही शादी से उपजा विवाद दिनोदिन जोर पकड़ता जा रहा है। जिले के एक इंका पदाधिकारी ने शादी के दौरान इंका-कार्यालय पर हुई रोशनी पर नुक्ताचीनी करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सजग नागरिक मंच के नेता और पूर्व मंत्री नरेश जौहरी ने शाही शादी में प्रदर्शित वैभव को वर्षों पूर्व दफनाये गये सामंतवाद के मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश निरूपित करते हुए केंद्र सरकार से सिंधिया व प्रदेश मंत्रिपरिषद से बालेंदु शुक्ल व शिवप्रताप सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। मंच ने विरोध दर्ज करने के अभियान के तहत उपवास, विधायकों से संपर्क, जन जागरण रैली, पोस्टर, दीवारों पर नारेबाजी, नुक्कड़ सभाओं, राज्यपाल व राष्ट्रपति को ज्ञापन के अलावा बजट सत्र में ग्वालियर से दिल्ली तक की पदयात्रा का कार्यक्रम तैयार किया है।

सिंधिया के करीबी लोग इन दिनों शाही शादी को सादगीपूर्ण निरूपित करने के लिए बंबई में गत दिनों हिंदुजा घराने में हुई ऐश्वर्यमयी शादी की मिसाल दे रहे हैं जो इस शादी से कई कदम आगे थी। इन लोगों का तर्क है कि काठ के मंडप तले हुई शादी को शताब्दी की शादी निरूपित करना ही गलत है। इन लोगों की मान्यता है कि सिंधिया विरोधियों को ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि ग्वालियर के लोगों ने विवाह में स्वयंस्फूर्त हिस्सा लिया। १२ दिसंबर को नवयुगल का लाखों की संख्या में उमड़कर पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया और महाराज की असीम लोकप्रियता व उनके प्रति आदर व निष्ठा पर मुहर लगा दी।

शाही शादी के विवाद की गंभीरता का आकलन इससे किया जा सकता है कि संबंधित तमाम रिपोर्टें प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी गयी हैं। शादी में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग व खर्च के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने कतिपय नजदीकी सांसदों से भी जानकारी ली है। भोपाल में जब प्रधानमंत्री का ध्यान ग्वालियर स्टेशन पर टाइल्स लगाने की ओर आकृष्ट किया गया, तो उन्होंने प्रश्न को 'देखूंगा' कह कर टाल दिया। इसके बावजूद अनेक लोगों का कयास है कि शाही शादी का विवाद सिंधिया के राजनीतिक पराभव का बायस बन सकता है।

—सुधीर सक्सेना

■

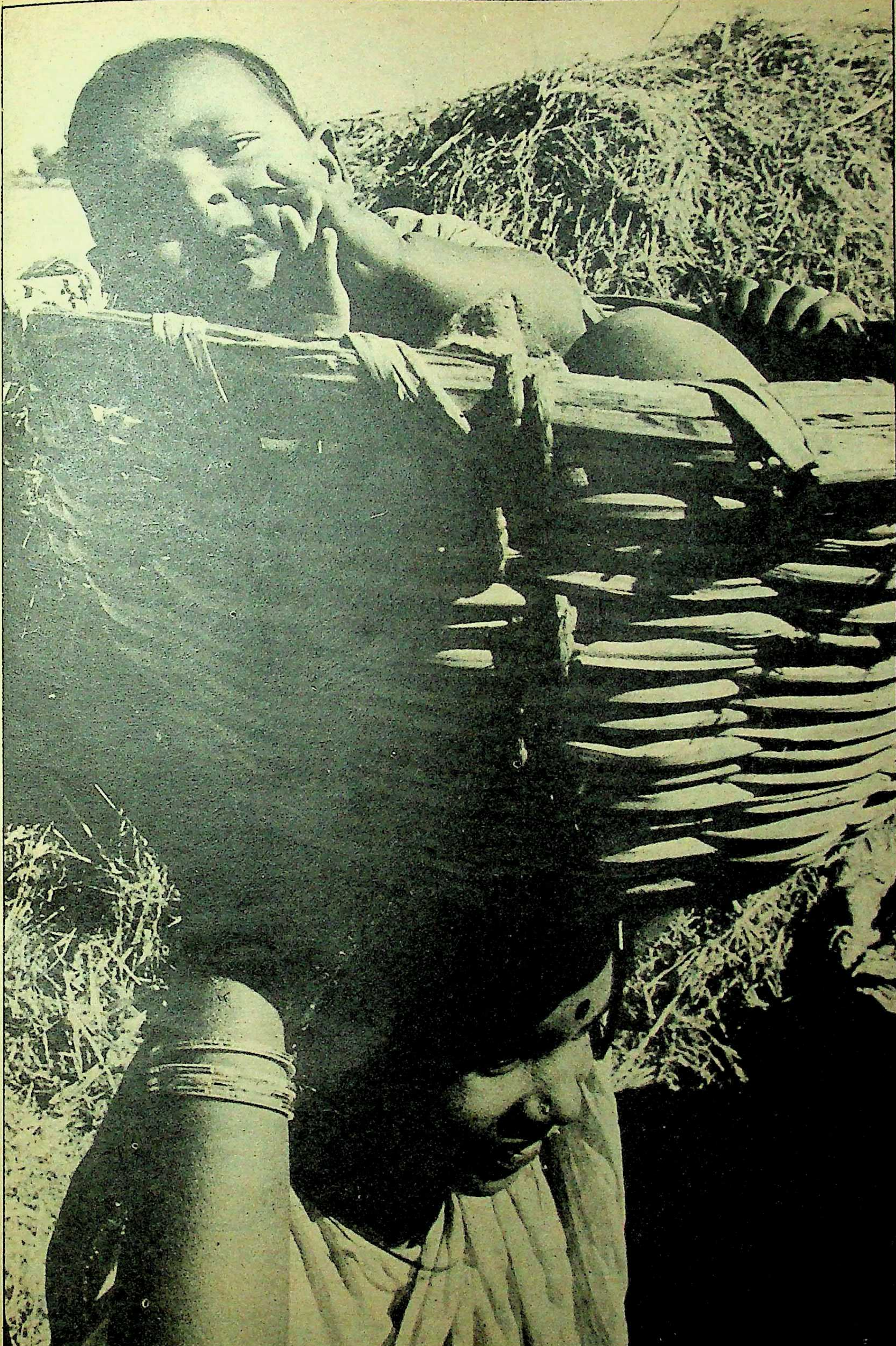

जिन टोकरों से गगन-चुम्बी इमारतों का निर्माण होता है, उन्हीं टोकरों में देश का अधिकांश बचपन भी पलता है। मानव संसाधन मंत्रालय और २१ वीं सदी में देश को ले जानेवाले लोगों के पास टोकरियों में पलने-वाले देश के इस भविष्य के लिए हो सकता है योजनाएं हों, लेकिन वे उस तक पहुंचने से पहले ही चुक जाती हैं। इसीलिए आगे चलकर ये शिशु देश के लिए बोझ बन जायें, तो इसमें मातृत्व के सुख से प्रफुल्लित उस मां का क्या दोष, जिसके लिए ये बोझ नहीं, बल्कि जिंदगी के बोझ को हल्का करने वाले आशा के फूल हैं।

छाया : बी०एल० राणा

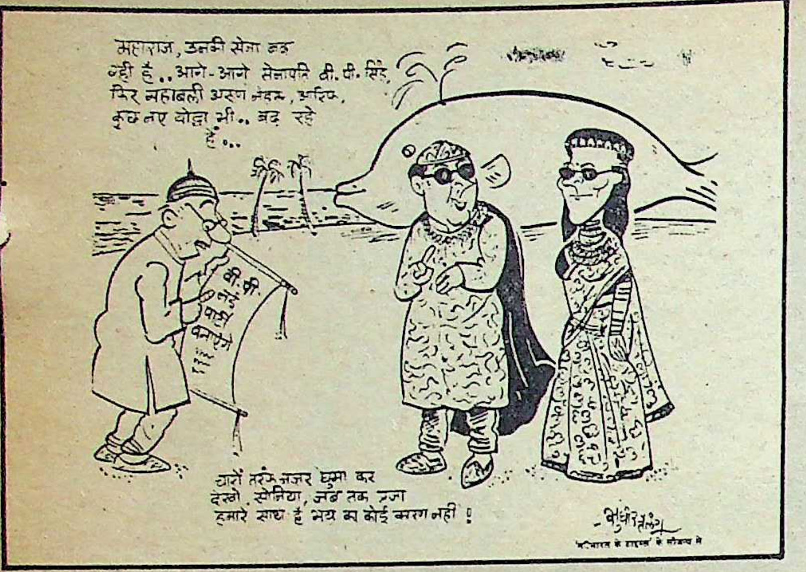
महाराज, उनकी सेना बढ़ रही है.. आगे-आगे सेनापति वी.पी. सिंह, फिर महाबली अरुण नेहरू, आरिफ, कुछ नए योद्धा भी.. बढ़ रहे हैं...
वी.पी. नई पार्टी बनाएंगे
चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, सोनिया, जब तक प्रजा हमारे साथ है भय का कोई कारण नहीं !
-सुधीर तैलंग

'नवभारत टाइम्स' के सौजन्य से

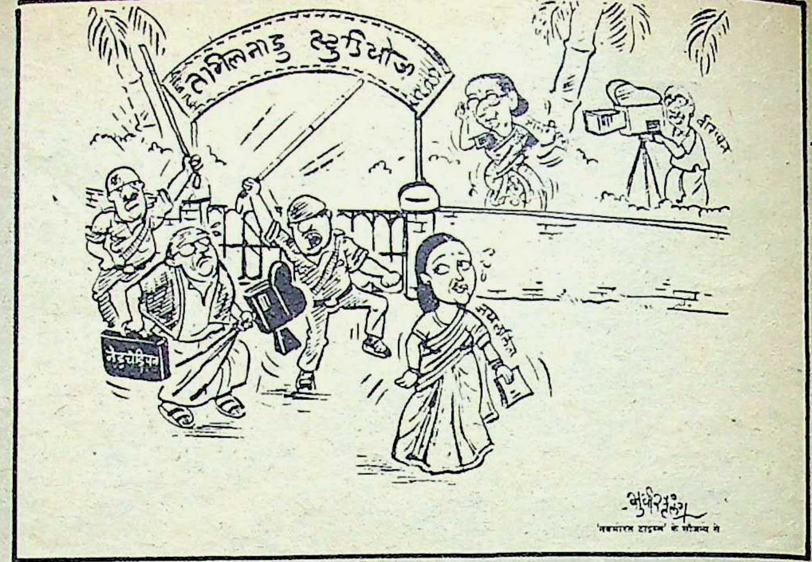
तमिलनाडु स्टुडियोज
नेडुचेझियन
जयललिता
वीरप्पन
-सुधीर तैलंग

'नवभारत टाइम्स' के सौजन्य से

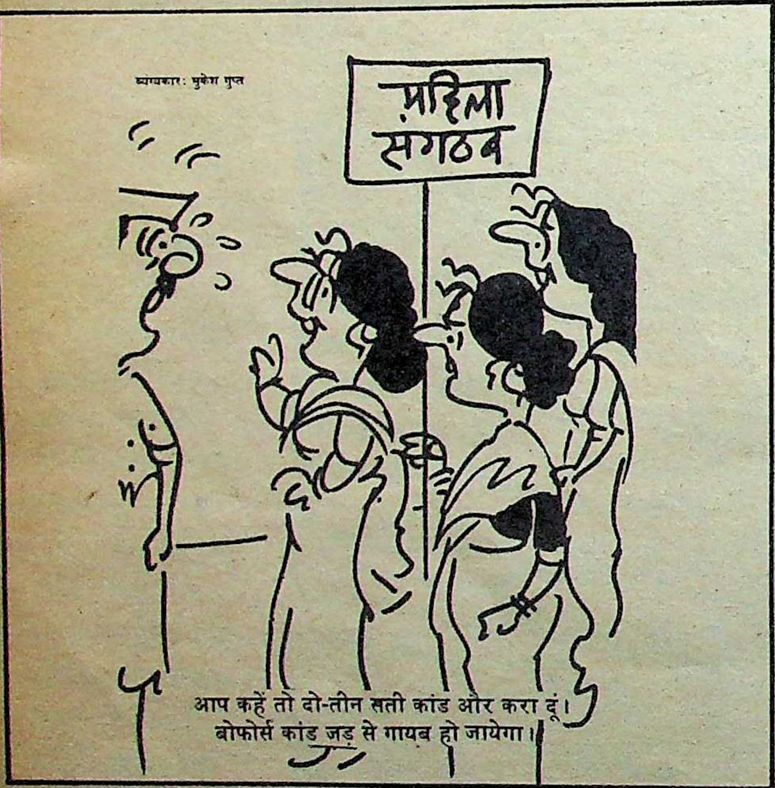
व्यंग्यकार: मुकेश गुप्त

महिला संगठन
आप कहें तो दो-तीन सती कांड और करा दूं। बोफोर्स कांड जड़ से गायब हो जायेगा।

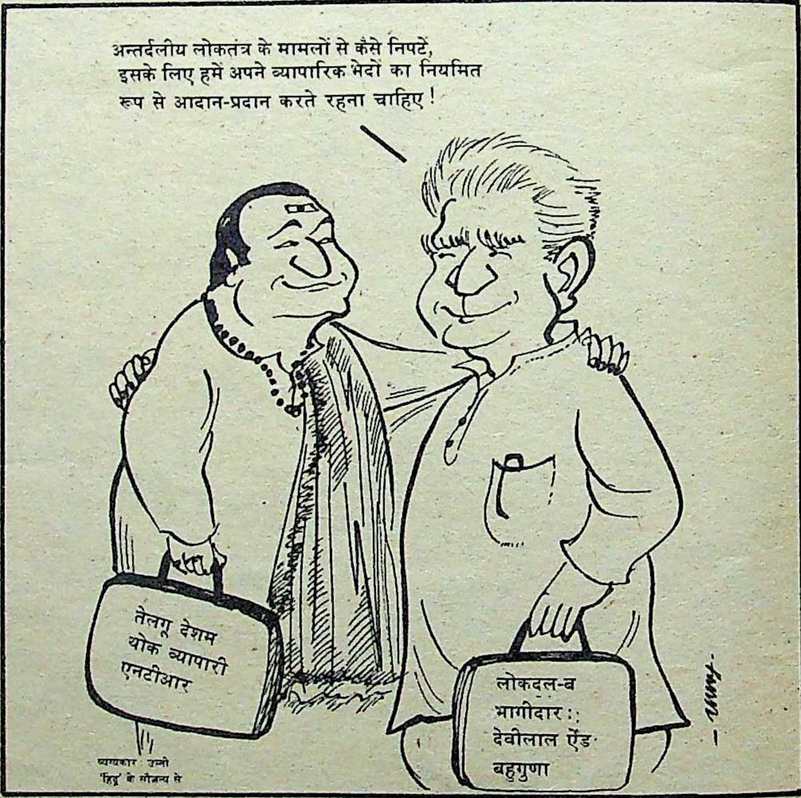
अन्तर्दलीय लोकतंत्र के मामलों से कैसे निपटें, इसके लिए हमें अपने व्यापारिक भेदों का नियमित रूप से आदान-प्रदान करते रहना चाहिए !
तेलगू देशम थोक व्यापारी एनटीआर
लोकदल-ब भागीदार: देवीलाल ऐंड बहुगुणा

व्यंग्यकार: उन्नी
'हिंदू' के सौजन्य से

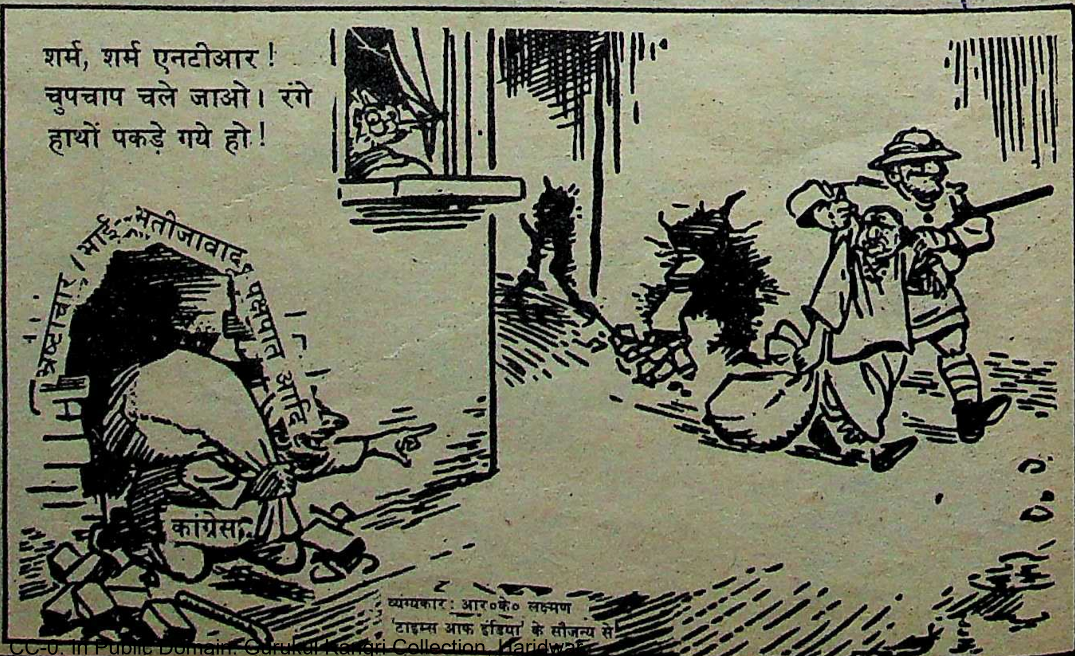
शर्म, शर्म एनटीआर ! चुपचाप चले जाओ। रंगे हाथों पकड़े गये हो !
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात आदि
कांग्रेस

व्यंग्यकार: आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य से

हाऽऽ!

साँस साँस में ताज़गी
साँस साँस में आत्मविश्वास

super fresh
Cibaca* Top
toothpaste
A Quality Product Of HINDUSTAN CIBA-GEIGY
super fresh
Cibaca* Top
toothpaste

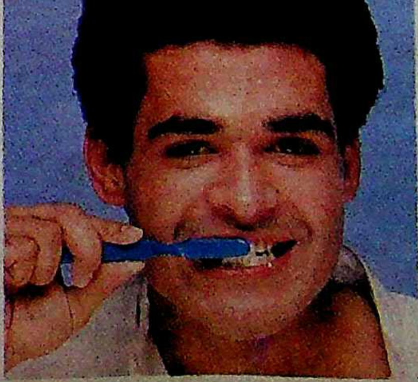

सिबाका टॉप का विशेष फैलनेवाला तत्व फ़ौरन आपके पूरे मुँह में फैलकर दांतो में सड़न पैदा करनेवाले क़ीटाणुओं का नाश करता है और साँस की दुर्गन्ध को रोकता है— आपके मुँह और दांतों को पूरी तरह साफ़ करते हुए आपकी साँसों को भरपूर ताज़गी से भर देता है.

यानी, सिबाका टॉप से—साँस साँस में ताज़गी साँस साँस में आत्मविश्वास. ऐसे-हा ऽऽ!

सिबाका टॉप
दूथपेस्ट

क्वालिटी उत्पादनों के निर्माता
हिन्दुस्तान सीबा-गायगी लिमिटेड

RCA/CT/204/88-HN-C

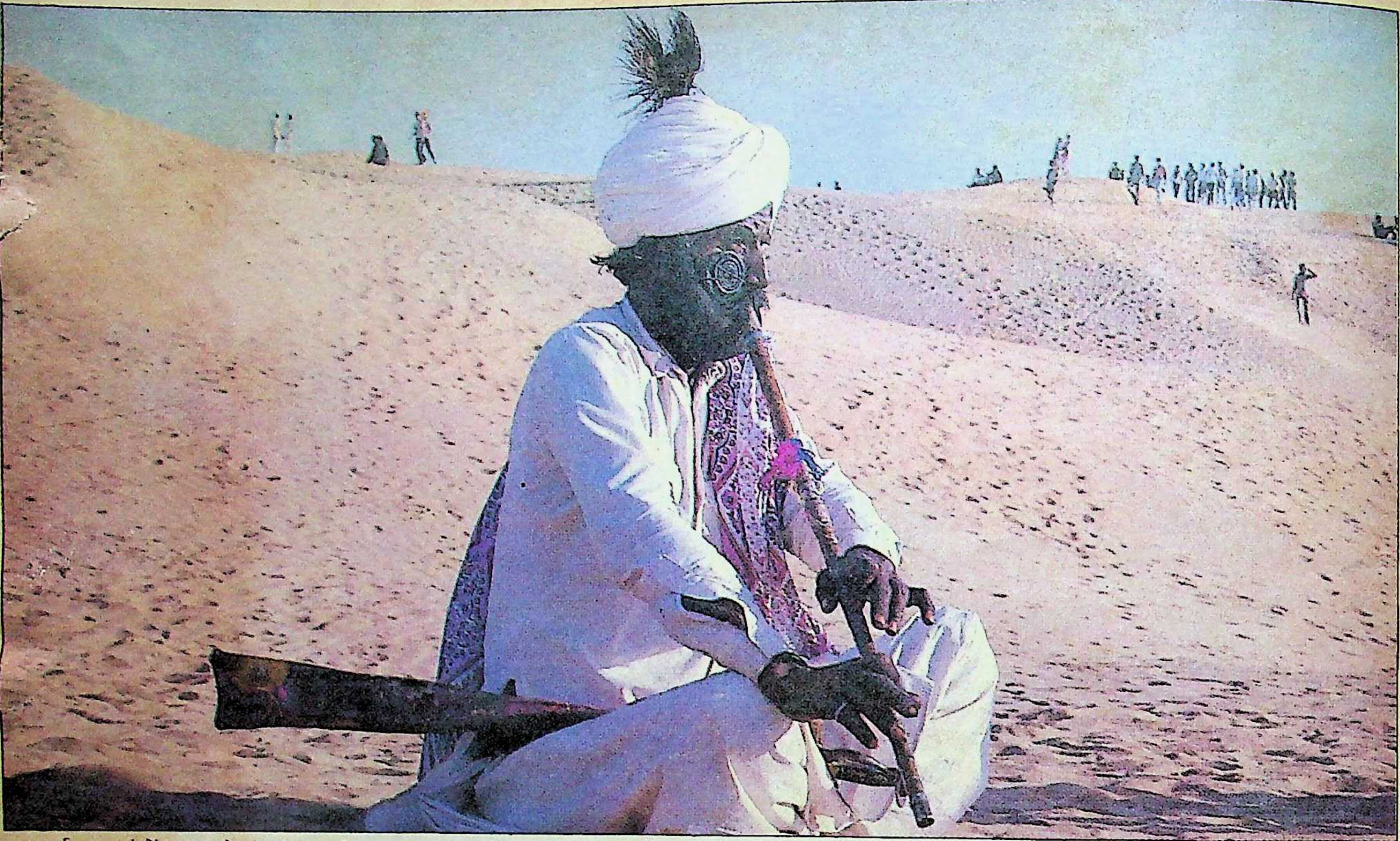

आश्चर्यजनक मूंछों वाला और 'नड' का दुर्लभ कलाकार : 'नड' बजाता करणा भील

छाया : ओम सैनी

विश्व प्रसिद्ध मूंछों वाला व्यक्ति

कटे सिर का रहस्य

जैसलमेर का करणा भील जीते जी तो चलता-फिरता एक आश्चर्य था ही, अब उसकी हत्या के बाद उसका गायब कटा सिर विश्व चर्चा का विषय बन गया है। छह फुट लंबी अपनी मूंछों के कारण करणा भील का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अंकित है। वह लोकवाद्य 'नड' का अच्छा कलाकार भी था। वह अपनी दो हसरतें पूरी करना चाहता था—एक थी, विदेश यात्रा और दूसरी थी, गोरी मेम से शादी करने की। उसे अपनी जान का खतरा था और इस खतरे की जानकारी प्रशासन और पुलिस दोनों को थी, फिर भी हत्यारे करणा भील का दिन दहाड़े सिर काटकर फरार हो जाने में सफल हो गये। पुलिस हत्यारों और कटे सिर का पता क्यों नहीं लगा पा रही? प्रस्तुत है, करणा भील के बहुरंगी जीवन की अंतरंग कथा :

वह प्रायः अपने निकटतम परिचितों से कहता था कि उसे जान का खतरा है, उसके दुश्मन एक-न-एक दिन उसका सिर काटकर पाकिस्तान ले जायेंगे। इसीलिए वह अपने पास हमेशा तेज धारवाला फरसा, तलवार, कटार तथा लाठी रखता था। जान के खतरे के कारण ही वह जबरन वायुसेना के स्थानीय मुख्यालय के द्वार के बाहर रहा करता था। काम की तलाश में सुबह काफी चहलपहल होने के बाद ही जाता और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता। उसकी आशंका ठीक ही निकली और २ जनवरी को दिनदहाड़े दोपहर बाद साढ़े तीन बजे दुश्मनों ने घात लगाकर उसकी हत्या कर दी। करणा को पता भी नहीं चला और एक ही वार में खच्च से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके हथियार फरसा, तलवार, कटार, लाठी किसी काम न आ सके।

बहुरंगी व्यक्तित्व : इसी के साथ जैसलमेर के लिए करणा भील इतिहास की चीज होकर रह गया। करणा भील के जीतेजी जैसलमेर के निवासियों ने उस पर शायद ही कभी गर्व किया हो। पर यह सच है कि जैसलमेर आनेवाले पर्यटक के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केन्द्र था, 'करणा भील'। अपनी मूंछों की लम्बाई के लिए उसका नाम विश्व प्रसिद्ध 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स' में है। लोकवाद्य 'नड' बजानेवाला वह बेहतरीन कलाकार था। इसके अलावा संभवतः वह दुनिया का अकेला इंसान था जो सिर पर मन्दिर लेकर

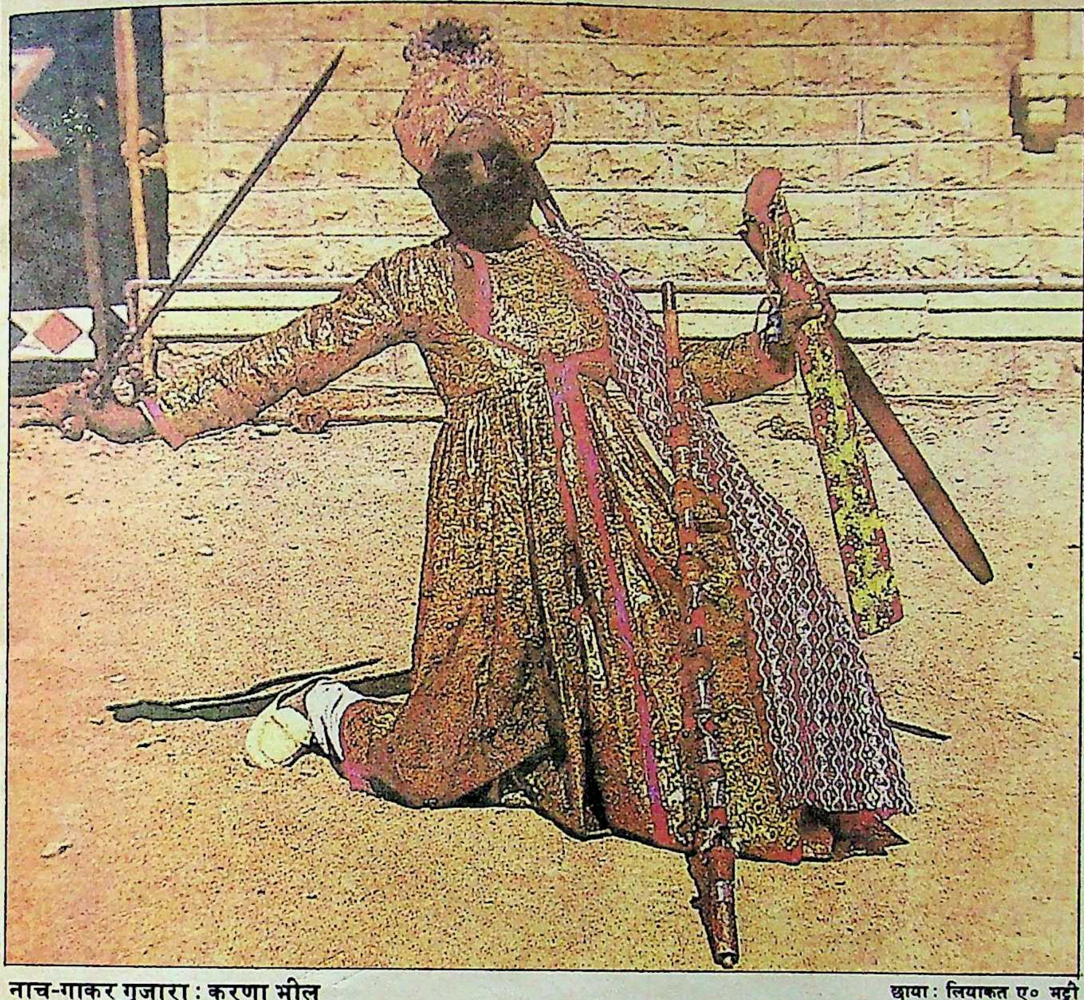

नाच-गाकर गुजारा : करणा भील

छाया : लियाकत ए० भट्टी

चलता था। सिर पर अपनी पगड़ी के बीच शिव और हनुमान की मूर्तियां रखता था और पगड़ी पर कृष्ण की तरह मोरपंख लगाता था। जिद्दी व अक्खड़ मिजाज, शौकीन और रंगीन तबियत, उम्र ६० साल, कद सवा छह फुट, काला रंग, सफेद कुर्ता, सफेद लेवटा, सफेद साफ़ा, कमर पर रंगोन कमरबन्द, पूरे गालों पर फैली छह फुटी लम्बी जलेबी जैसी मूंछोंवालों करणा अपने विचित्र व्यक्तित्व के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता था। बदन पर इत्र लगाना व छाती पर चमड़े की जाकेट पहनना उसका प्रिय शगल था।

करणा विचित्रताओं और विरोधाभासों की प्रतिकृति था। रिकार्ड पुरुष व लोकगायक करणा के व्यक्तित्व का दूसरा और भयानक चेहरा था, उसका भूतकाल। नये रूप में विश्वख्याति अर्जित करनेवाला 'करणा भील' इससे पूर्व हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास काट चुका था और उससे भी पहले वह भयानक डकैत था। लेकिन डकैती का कार्यक्षेत्र सीमा पार पाकिस्तान में होने के कारण राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं कर सकी।

राजस्थान के सुदूर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश जैसलमेर के बम्बारा गांव में जन्मे करणाराम ने जब युवावस्था में प्रवेश किया, तो उसने गांव में लोकगीतों में तत्कालीन डाकू इमापुरी तथा लालपुरी के किस्से सुने थे। इन गीतों को सुनकर उसे लगता कि वह भी कुछ कर दिखायें, तो उसके भी गीत इसी तरह औरतें घर-घर में गायेंगी। इसी चाहत ने उसे डाकू बना दिया और जीवन का बेहतरीन समय उसने इसी काम में लगाया। इसी चाहत में गर्व की प्रतीक मूंछों को उसने कभी काटा नहीं और बढ़ने दिया। इन मूंछों को सहेजने-संवारने में उसे काफी वक्त लगाना पड़ता, पर उसे गर्व था कि पूरे इलाके में उसकी जैसी मूंछें किसी की नहीं थीं। यह तो उसे बहुत बाद में पता चला कि उसके जैसी मूंछ दुनिया भर में किसी के पास ही नहीं है।

प्रेमी : जहां कुछ कर दिखाने की चाहत ने उसे डाकू और बड़ी मूंछोंवाला रिकार्ड पुरुष बनाया, वहीं अपनी 'सिन्धी' प्रेमिका लाली को रिझाने की चाहत में उसने 'नड' बजाना सीखा। 'नड' मूल रूप से पाकिस्तानी लोकवाद्य है जो सुपारी या कंगूर की लकड़ी से बनता है। कहा जाता है कि सिन्ध में तो इसे औरतें भी बजाती हैं। जैसलमेर में सिर्फ एक ही नडवादक है 'धन्ने खां'। करणा ने इसी धन्ने खां से नड बजाना सीखा था। बाद में वह नड बजाते समय अपनी उसी प्रेमिका 'लाली' के गीत गुनगुनाया करता। उसने लाली से शादी नहीं की थी। वह कहता था कि लाली उसकी प्रेमिका है और प्रेमिका पत्नी बनाने के लिए नहीं होती।

कहते हैं कि करणा और उसके साथी देशभक्ति की भावना के कारण सीमा पार डकैतियां डाला करते थे। पुलिस उप-अधीक्षक कन्हैयालाल बताते हैं कि असल में इस इलाके में लुट जाने जैसा लोगों के पास होता ही क्या है, इसी कारण पहले से ही यह परम्परा रही है कि इस इलाके के डकैत गुजरात तथा सिन्ध (वर्तमान में पाकिस्तान में) में डकैती डाला करते थे। यह परम्परा आजादी के बाद भी चालू रही। इससे एक लाभ तो डकैतों को यह होता था कि स्थानीय पुलिस उन्हें तंग नहीं करती थी और स्थानीय निवासियों की दुश्मनी भी उन्हें मोल नहीं लेनी पड़ती थी। कन्हैयालाल ने बताया कि अब तो डकैत रहे ही नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में जरायमपेशा प्रवृत्तिवाले लोगों का रुझान डकैती के बजाय तस्करी की ओर अधिक है।

निरन्तर अकाल पड़ना जैसे जैसलमेर की नियति है। यहां अकाल पड़ने के स्थान पर वर्षा होना चर्चा का विषय होता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग डकैती और तस्करी जैसे कृत्यों की ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। सीमा पारकर डकैती डालने में या तस्करी करने में उन्हें मदद करती है, राजस्थान की रेतीली टीलोंवाली सीमा तथा सीमा सुरक्षा बल की कमजोर निगरानी। जवानी में डाकू बने 'करणा' के लिए सीमा पार डकैती के अलावा एक आकर्षण था, उसकी कथित प्रेमिका 'लाली'। दोनों की यह प्रेमलीला कितनी लम्बी चली यह तो पता नहीं, लेकिन लीला के प्रेम में मगन हो करणा ने प्रेमगीत मरते दम तक गाये थे। पिछले चार-पांच सालों से वह अपने कार्यक्रम देते समय नडवादन के अलावा नाचने भी लगा था। विभिन्न लोकगीतों पर सजा-संवरा 'करणा' साठ साल की उम्र के बावजूद रोजी-रोटी के लिए नाचने को मजबूर था।

इलियास की हत्या : जवानी भर 'लाली' के गीत गाता, डकैती डालता, हत्याएं करता, करणा जब चालीस की उम्र तक आते-आते थकने लगा, तो उसने पिथोडिया गांव के पास खेती के लिए जमीन ले ली। कहते हैं कि वह खेत बहुत उपजाऊ था तथा इलाके में जो भी थोड़ी-बहुत बारिश होती, वह पानी उसके खेतों की तरफ ही आता। इसलिए वहां फसल जोरदार होती थी। १९७४ में अकाल पड़ने पर करणा मजदूरी करने जैसलमेर आ गया था। १९७५ में वापस लौटने पर उसने देखा कि उसके खेत पर 'अलाबक्श' ने बुवाई कर दी है। इस पर करणा ने अलाबक्श को बांधकर खेत पर डाल दिया। यह खबर फैलने पर गांव के अन्य लोग उसके पूर्व साथी इलियास सहित अलाबक्श को छुड़ाने आये। इलियास ने करणा की धमकियों की परवाह न करते हुए अलाबक्श के हाथ-पांवों की रस्सियां खोल दीं, इस पर गुस्से से पागल करणा ने इलियास को गोली मार दी। आधे घन्टे बाद इलियास ने वहीं दम तोड़ दिया। इसी हत्या के अपराध में करणा को आजन्म कारावास की सजा हुई थी। यह भी कहते हैं कि खेत पर हुए झगड़े का मूल कारण कोई पटवारी था, जिसने करणा की अनुपस्थिति में वह खेत 'अलाबक्श' के नाम आवंटित कर दिया था।

जेल में : कहते हैं कि जवानी में सवा छह फुट लम्बा कद्दावर जवान 'करणा' इतना ताकतवर था कि ऊंट के नीचे कंधा लगा कर उसे उठा देता और

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्ष्या भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्ष्या के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठाले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा शरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यिब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' बिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के त्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्ष्या मंडराती है आसपास। याद रखिये वो ावधान-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

घर के आगे करणा भील का परिवार

गोल चकरी लगवा देता। इसी ताकत और जिजीविषा का प्रदर्शन उसने आजन्म कारावास के दौरान किया, जब उसने नाखूनों से जैसलमेर कारागृह की दीवार खुरच-खुरचकर, उसमें पत्थर निकालकर भागने का रास्ता बना लिया था। ऐन मौके पर पकड़े जाने के बाद करणा को जोधपुर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। कहते हैं कि करणा की अद्भुत जिजीविषा से आतंकित हो जोधपुर जेल में उसे कमजोर करने के लिए दो बोतल खून निकाल लिया गया था। बाद में जेल-प्रवास में वह 'नड' बजाकर अपना समय काटता। उसकी मूंछों और नडवादन ने जोधपुर जेल प्रवास के दौरान ही ख्याति पायी थी। जोधपुर जेल से निकलने के बाद करणा पहलेवाला कद्दावर, जुझारू, अपराध-प्रवृत्ति का करणा नहीं रहा, बल्कि लोक-कलाकार 'करणा भील' के रूप में बदल गया। दुर्दान्त डाकू और हत्यारे करणा को जेल-प्रवास ने अन्दर से जर्जर कर डाला था। जेल से निकलने के बाद वह अपने गांव जाने की जगह जैसलमेर में ही बस गया और नडवादन कर अपनी मूंछ खोलकर दिखाने व फोटो खिंचाने की अच्छी कीमत वसूलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा।

करणाभील

> करणा विचित्रताओं और विरोधाभासों की प्रतिकृति था। रिकार्ड पुरुष व लोकगायक करणा के व्यक्तित्व का दूसरा और भयानक चेहरा था, उसका भूतकाल।

हत्या : जेल से निकलने के बाद वह बदले की आशंका से त्रस्त रहा और इसी कारण वापस पिथोडिया जाने की बजाय उसने जैसलमेर में ही बसना उपयुक्त समझा। सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने पास हमेशा तेज धारवाला फरसा व कटार रखता। वह चाहता था कि उसे सुरक्षा के लिए बन्दूक का लाइसेंस मिल जाये, लेकिन पूर्व-अपराधी होने के कारण उसे लाइसेंस नहीं मिला। वह अक्सर अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करते समय कहता कि तीन-चार लोगों की उसे परवाह नहीं है। इतने लोगों को तो वह अकेला फरसे से ही निबट लेगा। लेकिन दो जनवरी को भरी दोपहर जब घात लगाकर उस पर हत्यारों ने हमला किया, उस समय वह ऊंट गाड़ी पर घर की गायों के लिए चारा लेकर लौट रहा था। नीरज होटल के पिछवाड़े सुनसान में अपनी मस्ती में मस्त गुनगुनाते करणा को पता भी नहीं चला कि कब मौत दबे पांव उसके पीछे आयी और कब उसका सिर धड़ से अलग हो गया। घटनास्थल से उसका घर तीन फर्लांग और शहर कोतवाली से सिर्फ ३०० मीटर दूर था। लेकिन भरी दुपहर में किसी को करणा की हत्या की कानों-कान खबर न हुई। उसकी लाश ऊंटगाड़ी पर एक हाथ से ऊंट की रस्सी थामे घास पर इस तरह से पड़ी थी, मानों वह घास पर सो रहा हो। मार्ग-परिचित ऊंट अपने मालिक के शव से लदी घास से भरी गाड़ी को लेकर घर पहुंचा। उस समय घर पर उसका चौथे नम्बर का पुत्र टीकू राम ही था। करणा की सिर कटी लाश को देखकर घर में हाहाकार मच गया। वह भागा-भागा पुलिस थाने गया और देखते-देखते समूचे जैसलमेर में करणा की हत्या की खबर फैल गयी। सुननेवालों की एक ही प्रतिक्रिया थी, करणा का डर ठीक ही निकला, आखिर बदला ले ही लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्यारों की संख्या दो से तीन के बीच है। हत्यारे करणा के सिर के साथ-साथ उसका फरसा भी ले गये। अभी यह पता नहीं चल सका है कि करणा की हत्या करने के लिए हत्यारों ने कहीं करणा का ही फरसा तो इस्तेमाल नहीं किया।

मामले की जांच कर रहे पुलिस उप-अधीक्षक कन्हैयालाल के अनुसार एक हत्यारा दूर से आसपास की निगरानी कर रहा था और दूसरे हत्यारे ने बबूल की झाडी के पीछे से घात लगाकर करणा पर हमला किया। करणा का सिर लेकर भागते हुए हत्यारे तालब खां सरपंच के घर के पास पहुंचे (तालब खां तस्करी के आरोप में रासुका में बन्द रह चुका है)। वहां खड़े जोंगे में बैठकर वे सब पिथोडाई स्थित इलियास की कब्र पर वह सिर लेकर पहुंचे। कब्र से पांवों व जूतों के चिन्ह तथा रक्त के निशान पुलिस ने बरामद किये हैं। इसके पश्चात उन्होंने पास की पशुओं की पानी पीने की खेली (हौदी) में हाथ-पांव व कपड़े धोये तथा पिथोडाई से अब्दुल का ऊंट लेकर चले गये।

पुलिस हत्यारों को पकड़ने में असफल रही है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करती कि करणा का सिर लेकर हत्यारे सीमा पार कर चुके हैं, जबकि जैसलमेर के स्थानीय निवासियों का मानना है कि हत्यारे करणा का सिर लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल की आंखों में धूल झोंककर सीमा पार करना वहां बच्चों के खेल जैसा है। यहां तक कि सीमा पार बारातों का आना-जाना वहां के लिए कोई नयी बात नहीं है।

बताया जाता है कि इलियास की हत्या के बाद उसके बड़े लड़के फाटू खां ने बदला लेने की कसम खाकर काले कपड़े पहन लिये थे। इलियास की दो बहनों के अलावा बाकी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। फाटू खां अपने दो छोटे भाइयों कायम खां तथा फोतिया को बहनोई रिडमल के पास छोड़कर बाद में काम की तलाश में पाकिस्तान चला गया था। पुलिस को इलियास के बड़े लड़के फाटू खां तथा बहनोई रिडमल की तलाश है। उनके अनुसार इस हत्या काण्ड में इन दोनों के अलावा इलियास के भतीजे भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस जब पूछताछ के लिए पिथोडाई पहुंची, तो उसे गांव में कोई भी पुरुष नहीं मिला। रिडमल का पूरा परिवार गायब था। इलियास के दोनों छोटे लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। इस काण्ड में अलाबक्श के परिवार के सम्मिलत होने की आशंका से जांच प्रभारी पुलिस उप-अधीक्षक कन्हैयालाल इनकार करते हैं।

कन्हैयालाल ने बताया कि इलियास के मामले

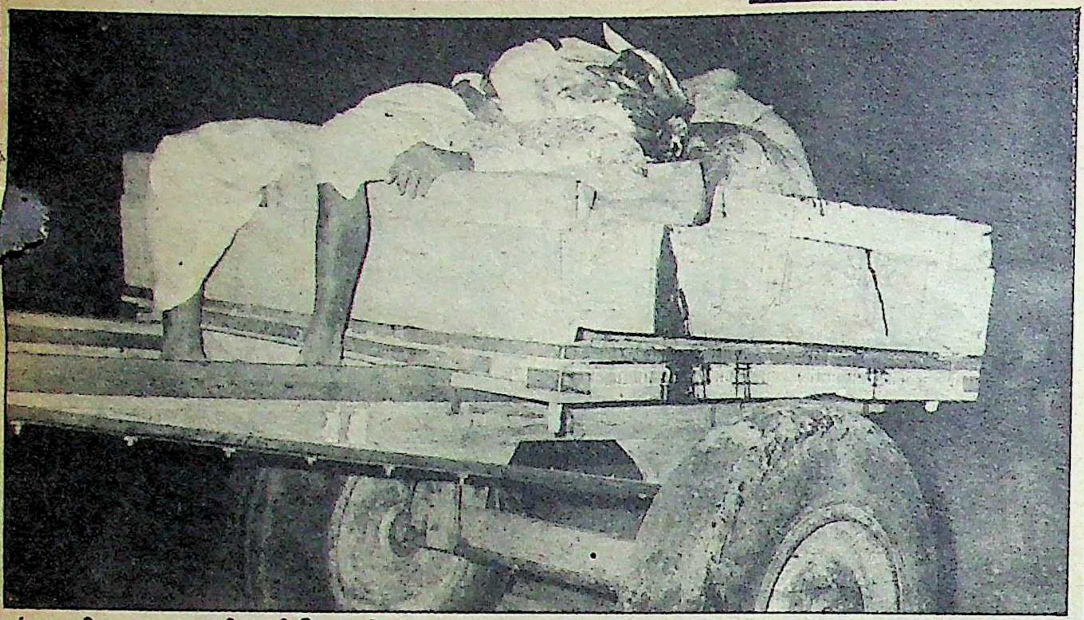

ऊंट गाड़ी पर करणा भील कीसिर कटी लाश

पुत्र कायम ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि घर पर बदला लेने की चर्चा यदाकदा होती थी, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि इसे अन्जाम किसने दिया तथा अंतिम योजना कब बनी?

करणा की विधवा पार्वती ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसके पति की हत्या तालब खां सरपच के यहां बनी थी तथा षड्यंत्र में शहर के सभी शक्तिशाली मुसलमान (कुख्यात मुसलमान तस्करों के लेकर) शामिल हैं। हत्यारों ने भागने के लिए तालब खां का जोंगा ही इस्तेमाल किया था, जबकि पुलिसवालों के मुताबिक हत्यारे पैदल भागते हुए पिथोडाई गांव के पास बनी 'इलियास' की कब्र तक गये थे।

करणा की मौत के बाद उसके परिवार के समक्ष जीवनयापन की समस्या पैदा ही गयी है। उसके छह लड़कों में से दूसरे लड़के हुक्मा का कत्ल मई, १९८७ में छोटे भाई हीरा ने कर दिया था तथा हुक्मा की लाश को घर के आंगन में गाड़कर अपनी भाभी के साथ फरार हो गया था। छह माह बाद २१ नवंबर, १९८७ को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, दोनों देवर-भाभी जेल में हैं। बड़े लड़के धनिया की आंख में मोतियाबिन्द है और चौथे लड़के टीकू के अलावा दोनों छोटे भाई भी अभी बहुत छोटे हैं।

हालांकि, जिलाधीश ललित के० पंवार ने आश्वासन दिया है कि करणा परिवार को राज्य सरकार से दस हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। इससे पूर्व वह करणा के परिवार सहित ६० लोक-कलाकारों के लिए कलाकार कालोनी में भूखण्ड आवंटित कर चुके हैं।

पुलिस अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और न ही उसे उन सूत्रों का कोई सुराग मिला है, जिसके जरिए वह करणा भील के कटे सिर का पता लगा सके। क्या विश्व स्तर पर चर्चित इस हत्याकांड के अभियुक्त पाकिस्तान चले गये हैं? सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सीमा पर कड़ी चौकसी का दावा करते हुए इस संभावना से इनकार करते हैं, लेकिन जानकार लोगों का दावा है कि हत्यारे पाकिस्तान जा सकते हैं और यदि वे पाकिस्तान चले गये हैं, तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर पाना भारतीय पुलिस के लिए आसान नहीं है।

छाया : अजंता स्टुडियो

– धीरज कुलश्रेष्ठ

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक
रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोजमर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर व नये रक्त के निर्माण द्वारा पूरे शरीर का पोषण करती **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा बहुमूल्य जड़ी-बूटियों, केसर, मोती आदि द्रव्यों से निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय, आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो पुरुषों को सदैव निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

स्थानीय विक्रेता से लें या
वी.पी. द्वारा मंगवायें।

राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
शाखाएं : दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

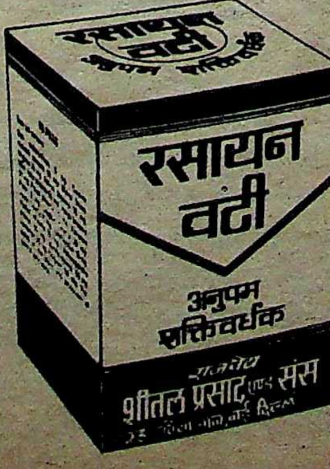

धनकुबेर पारसमल लोढ़ा

कलकत्ता के उद्योगपति शिकंजे में

लोढ़ा (इनसेट) के कब्जे में : पीयरलेस बिल्डिंग, कलकत्ता

क्या पश्चिम बंगाल के गैरबंगाली नये धनकुबेर पारसमल लोढ़ा ने वास्तव में वित्तीय कंपनी पीयरलेस, अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समैन, अमृतबाजार पत्रिका और युगांतर के इतने शेयर खरीद लिये हैं कि वह वस्तुतः इन प्रतिष्ठानों के मालिक बन गये हैं? व्यावसायिक जगत में हलचल मचा देनेवाले ये नये रईस पारसमल लोढ़ा कौन हैं और उन्होंने इतनी ताकत कैसे हासिल कर ली कि आज पश्चिम बंगाल के व्यावसायिक जगत से लेकर राजनीतिक दीर्घाओं तक में उनके नाम की धूम मची हुई है?

नवंबर माह के अंत में यह अफवाह जोरों पर थी कि पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण समाचार पत्र 'युगांतर' और 'अमृतबाजार पत्रिका' के स्वामित्व को एक गैरबंगाली व्यवसायी पारसमल लोढ़ा खरीदने जा रहे हैं तथा पीयरलेस और निक्को ग्रुप के शेयर का बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में है। 'युगांतर' और 'अमृतबाजार' ग्रुप के स्वामित्व बदलने की खबर से सारा समाचार-संसार हिल उठा। 'युगांतर' ग्रुप का स्वामित्व बदलने के मामले में पारसमल लोढ़ा का नाम सुनाई पड़ने के बाद बहुतों को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लोढ़ा 'अमृतबाजार' ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर तुहिनकांति घोष के घनिष्ठ मित्र हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में दोनों के बीच बड़ा अच्छा संबंध है, इसलिए शेयरों का बहुत बड़ा हिस्सा एक हाथ से दूसरे हाथ में भी जा सकता है। सुनने में आया है कि पीयरलेस पर कब्जा जमाने के मामले में लोढ़ा ने पी०सी० सेन और तुहिनकांति पर बड़ा भरोसा किया था। उन्हीं दोनों के कारण लोढ़ा पीयरलेस पर कब्जा करने में सफल हो सके। इससे जाहिर है कि लोढ़ा से तुहिनकांति की कहीं रजामंदी जरूर थी। अनुमान है कि इसी बहाने लोढ़ा से 'युगांतर' ग्रुप की दोस्ती बढ़ी।

लेकिन 'युगांतर' ग्रुप से पारसमल लोढ़ा का संबंध बहुत पुराना है। पारसमल के पिता मनोहर मल अमृतबाजार पत्रिका के वितरक और एजेंट थे। अतः 'युगांतर' ग्रुप से लोढ़ा परिवार का व्यावसायिक संबंध था। संभव है, पारसमल लोढ़ा ने भी बहुत सारे शेयर खरीद लिये हों। फिर उन्होंने 'युगांतर' ग्रुप को कर्ज भी दिया है तथा विभिन्न व्यावसायिक मामलों में लोढ़ा ने उनकी सहायता भी की है। इस नाते 'युगांतर' ग्रुप पर लोढ़ा का थोड़ा अहसान भी था।

पारसमल लोढ़ा द्वारा इस समाचार पत्र समूह के काफी शेयर खरीद लिये जाने की अफवाह इसलिए भी चल निकली, क्योंकि उन्होंने स्टेट्समैन के शेयर भी खरीदे। हालांकि, बाद में पारसमल ने स्टेट्समैन के शेयर बेचने चाहे थे। यहां तक कि उन्होंने उद्योगपति बिड़ला की तरफ से बंबई के एक धानढ्य व्यवसायी के सामने उन शेयरों को बेचने का प्रस्ताव भी रखा था।

लोढ़ा के 'युगांतर' अभियान की खबर को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक हलचल शुरू हो गयी। कहा जाने लगा कि जब तक तुषारकांति घोष जीवित रहेंगे, तब तक उन्हीं का नाम छपेगा और फिलहाल संचालन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में संचालक मंडल में फेरबदल किया जा सकेगा—तब लोढ़ा एकदम शीर्ष पर रहेंगे।

पारसमल लोढ़ा के युगांतर अभियान के बारे में कलकत्ते की पत्र-पत्रिकाओं के चुप रहने पर भी यह मामला अधिक दिन छिपा न रहा। पहली दिसंबर को युगांतर और अमृतबाजार पत्र समूह के संपादक और उस ग्रुप के चेयरमैन तुषारकांति घोष का एक वक्तव्य प्रमुखता से छपा। इसमें उन्होंने अमृतबाजार पत्र समूह के बिकने की खबर का खंडन

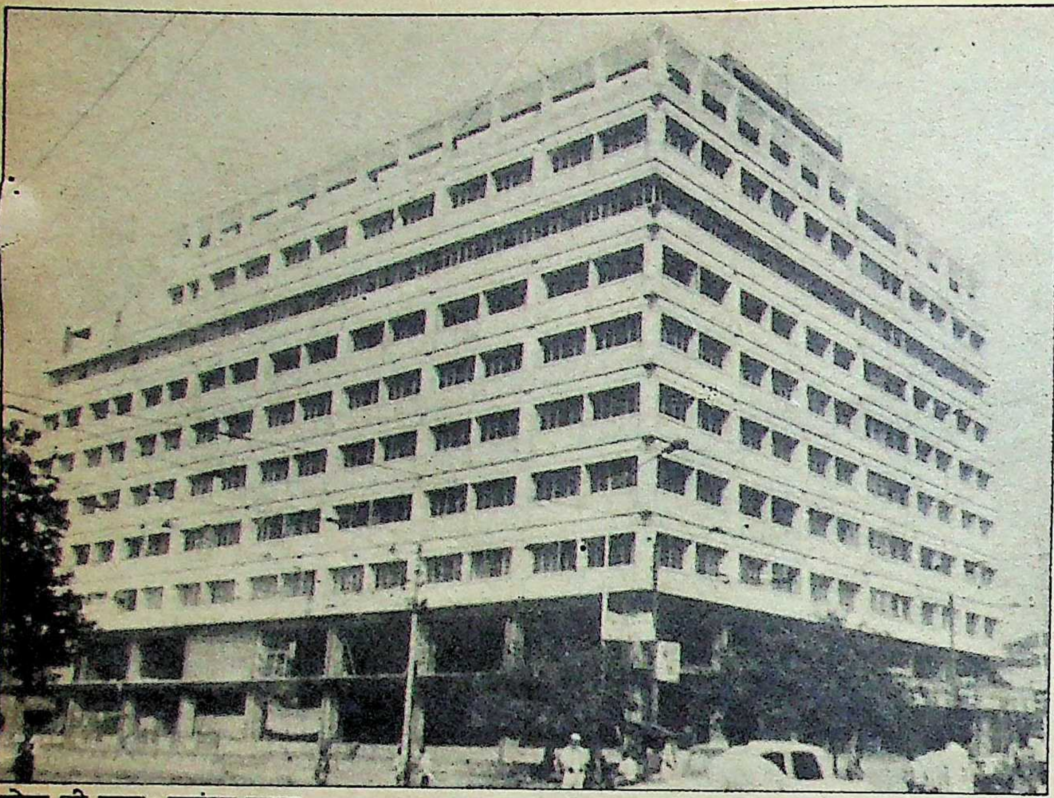

लोढ़ा की नजर : युगांतर हाउस

करते हुए कहा था कि यह घटना सही नहीं है। बहरहाल, इस मामले में पारसमल की भूमिका रहस्यमय बनी रही।

संभवत: इसी विवाद के बाद पारसमल लोढ़ा प्रकाश में आये। उनको लेकर अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। उनकी धनाढ्यता के कारण आयकर विभाग भी परेशान था। विभाग के लोगों ने कई महीने पहले कलकत्ते में उनके एक मित्र के घर में छापा मारा। बहुत से ऐसे कागजात मिलें, जिनका हिसाब-किताब से कोई संबंध नहीं था। पता चला कि प्रचुर संपत्ति के मालिक पारसमल लोढ़ा ने अनेक मामलों के हिसाब-किताब में गड़बड़ी की है। अनेक फर्जी कंपनियों का भी पता चला।

लोढ़ा कौन हैं? : रातोरात करोड़पति बननेवाले तथा समाचार पत्र जगत के जाने-माने समाचार और अमृतबाजार ग्रुप के लेनदेन के नायक के रूप में चर्चित पारसमल को लेकर आयकर विभाग और इनटेलिजेंस ब्यूरो को भी कम हैरानी नहीं थी। दस वर्ष पहले पारसमल लोढ़ा मामूली कार्पोरेट डिपाजिटर और रीयल एस्टेट ब्रोकर थे। तैंतीस वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में सर्वाधिक पूंजी-निवेश करनेवाले के रूप में कलकत्ते में अपना शीर्ष स्थान बना लिया है और २० फर्मों में उनकी कई करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। २१ अक्तूबर, १९५४ को जन्मे लोढ़ा के पिता का नाम है, मनोहरमल और माता का बनवारी देवी लोढ़ा। पिता अमृतबाजार पत्रिका के डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट थे। लोढ़ा परिवार की जड़ें राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हैं। सुजानगढ़ कलकत्ते के अनेक नामी-गिरामी व्यवसायियों का आदि निवास स्थान है। जिस समय पारसमल बालीगंज की रूगंटा अकादमी में पढ़ते थे, तभी से वह अपनी व्यावसायिक बुद्धि का परिचय देने लगे थे। विभिन्न विदेशी प्रकाशकों को पत्र लिखकर वह कमीशन पर पुस्तकें मंगाते थे और बाद में उन्हें मुनाफा लेकर बेच देते थे। सेंट जेवियर्स कालेज में पढ़ते समय वह उन प्रकाशकों के एजेंट बन गये थे।

जमीन-जायदाद और कार्पोरेट डिपाजिट के दलाल के रूप में पारसमल ने अपना जीवन शुरू किया। सुजानगढ़ के मूल निवासी होने के नाते उन्हें किसी से ऋण लेने या किसी तरह की आर्थिक सुविधा प्राप्त करने में सुजानगढ़ मूल के व्यवसायी हर समय उनकी मदद करते थे। धीरे-धीरे विभिन्न बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी उनका संपर्क हो गया। रीयल एस्टेट के दलाल के रूप में पारसमल फ्लैट या आफिस के क्रय-विक्रय और उनको किराये' पर देने का व्यवसाय करते थे। हर महीने किराये से मिलनेवाले कमीशन से उनकी आय अच्छी होने लगी। उनके एक संबंधी संसद सदस्य थे। उस सांसद ने उनका परिचय एक प्रभावशाली मंत्री से करा दिया था। पारसमल ने उसी परिचय से भरपूर लाभ कमाया। उस समय उन्हें कलकत्ता म्युनिसिपल कार्पोरेशन के नये मकान बनाने का कार्य मिल गया, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

व्यवसाय के क्षेत्र में सभी लोग जान गये कि पारसमल हर काम में 'हां' कह सकते हैं। फिर तो विभिन्न उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने पारसमल की क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया। उच्चाकांक्षी पारसमल ने बुद्धि का चमत्कार दिखाते हुए छत कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। उसी से उनका भाग्योदय हुआ। वह अनुपयोगी छत खरीदकर फ्लैट बनवाने और बेचने लगे। १९८२-८३ में उनका पहला प्रोजेक्ट था, एग्रो इंडस्ट्रीज के टोबैको हाउस के दो रूम बनवाने का। फिर तो कलकत्ते के अनेक मकानों की छतों के मालिक बनकर उन्होंने अपनी जय-यात्रा शुरू की। विशेषकर बड़ा बाजार में घने बमे इलाके में छतें मिल जाने से मानो रातोरात उनका भाग्य खुल गया।

अधिकांश मकान मालिकों ने छत बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें मकान से बहुत कम किराया मिलता था। इसलिए छत बेचकर उनको अच्छा पैसा मिलने लगा, तो उनको आपत्ति किस बात की होती? पारसमल लोढ़ा ने कुल ५० मकानों की छतें खरीदी थीं। इनमें पार्क स्ट्रीट का स्टीफेन कोर्ट और हेयर स्ट्रीट का निक्को हाउस उल्लेखनीय है। इन मकानों की छतों पर उन्होंने नयी-नयी आधुनिक इमारतें बनवाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचा। कलकत्ता कार्पोरेशन के अधिकारीगण कभी लोढ़ा के निर्माण कार्य में बाधक नहीं बने। लोढ़ा के इस काम के लिए कभी डिमालिशन स्क्वायड नहीं भेजा गया। कार्पोरेशन के कानून तोड़ने के मामलों में भी उन्हें न्यूनतम जुर्माना देना पड़ता था।

अब पारसमल लोढ़ा कलकत्ता शहर के नंबर एक डेवलपर कहलाने लगे। कलकत्ता कार्पोरेशन से उनका अच्छा संबंध इसमें बहुत काम आया। बड़े-बड़े ठेकेदार उनके पास दौड़ने लगे। बड़े-बड़े वकील उनके सलाहकार बन गये। यश और प्रतिष्ठा से तर लोढ़ा के सामने जमीन-जायदाद के मामलों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था।

बाद में तो पारसमल व्यवसाय के हर क्षेत्र में आदर्श बन गये। जमीन-जायदाद के व्यवसाय में तो उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की कि उम क्षेत्र के अन्य व्यवमायियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ समय पहले आयकर विभाग के लोगों ने उनके घर और दफ्तर पर छापा मारकर बहुत से कागजात जब्त किये। भूमि हस्तांतरण के मामलों में यह संदेह किया जा रहा है कि उन सौदों में पैसे के खूब लेनदेन हुए हैं, जिनका उन कागजात में उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा बागड़ी मार्केट के नवनिर्मित फ्लैटों की एक सौ चाबियां भी मिली हैं। अभी तक सारे फ्लैट नहीं बिके हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि वे सब मामले प्रीमियम से संबंधित हैं। १९८२-८३ में ही पारसमल लोढ़ा पार्क स्ट्रीट के क्वींस मैसन में चले आये। इसके अलावा टोबैको हाउस में भी उनका कार्यालय है। बताया जाता है कि इन दिनों उनका अड्डा निक्को हाउस में भी है। कुल मिलाकर उनका कारोबार खूब चल निकला है।

पीयरलेस पर कब्जा : पीयरलेस के स्वामित्व हस्तातरण के नाटक में मंच पर पारसमल लोढ़ा का प्रवेश काफी हद तक अप्रत्याशित था। १९८६-८७ में एक के बाद एक मुकदमों के कारण पीयरलेम का व्यवसाय बहुत कम हो गया। उस वर्ष उमका व्यवसाय मात्र २० करोड़ रुपए का हुआ था और पीयरलेस की आर्थिक नींव कमजोर थी। मुकदमे की जटिलताओं के कारण संचालन मंडल व्यवमाय चलाने में असमर्थ था।

१९८५ में पीयरलेस के प्रमुख कर्णधार बी०के० राय का निधन हो गया था। वैमी स्थिति में

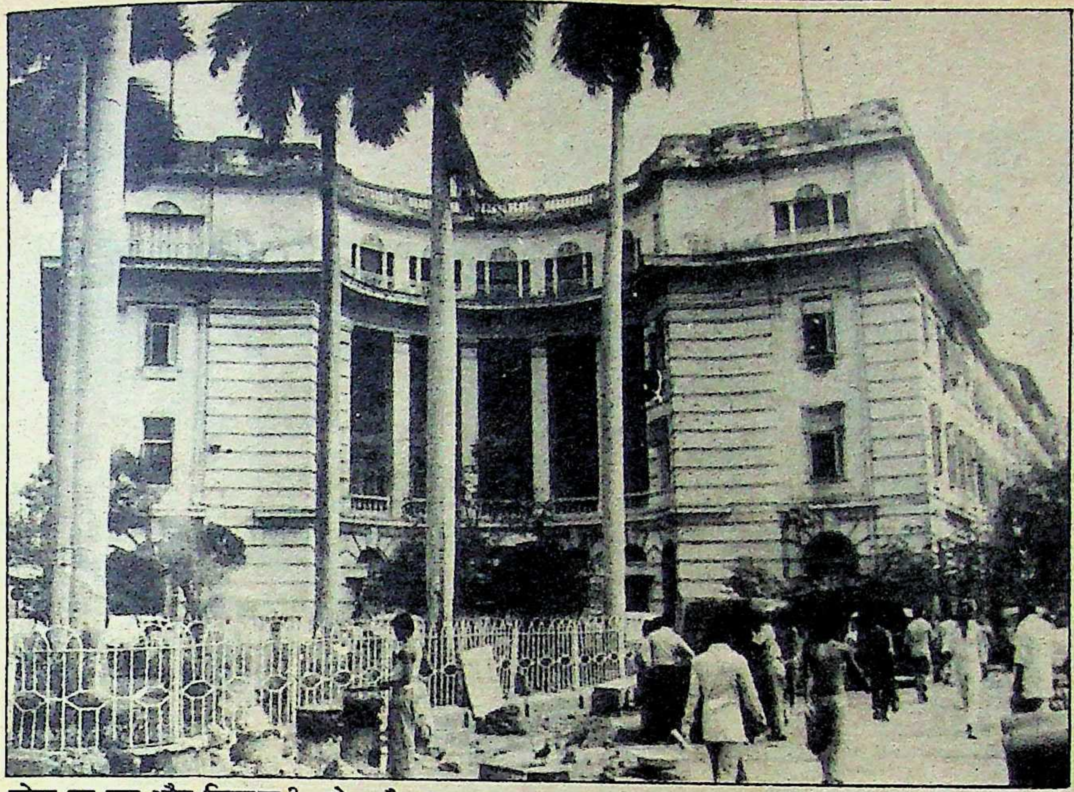

लोढ़ा का एक और निशाना ? : स्टेट्समैन हाउस

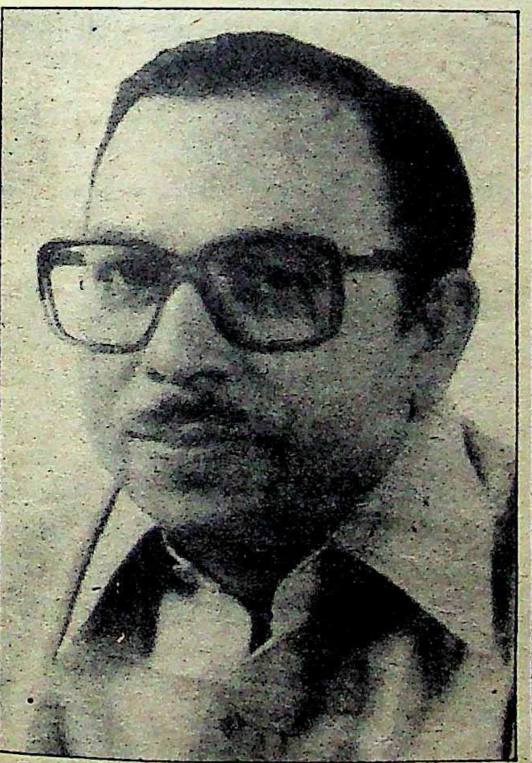

शक्तिहीन ? : एस०के० राय

उनके भाई एस०के० राय ने प्रतिष्ठान के उत्तरदायित्व से घबराकर अपने शेयर बेचने की घोषणा कर दी। शेयर के मालिक के रूप में राय सर्वोपरि थे। उनके पास ग्यारह हजार से अधिक के शेयर थे। तुहिनकांति के पास ३,५३०, ए०के० चटर्जी के पास ४१५ और पारसमल के पास ४०० शेयर थे। १७ जुलाई, १९८६ को निक्को हाउस के सर्वेसर्वा और अरुण नेहरू के साले राजीव कौल ने घोषणा की कि निक्को ग्रुप ने अकेले ही १८ प्रतिशत शेयर खरीद लिये हैं और संचालन के मामले में वह पीयरलेस की सहायता करेगा। उसी दिन लोढ़ा के विशिष्ट मित्र अमृतबाजार पत्रिका के प्रबंध निदेशक तुहिनकांति घोष और लोढ़ा की बहन कुमुद मित्र ने भी पीयरलेस के शेयर खरीदे। उसके बाद देखा गया कि ८० प्रतिशत शेयर के मालिक राय परिवार ने ५१ प्रतिशत शेयर बेच दिये। यहां तक कि स्वर्गीय बी०के० राय के भी कुल शेयर बिक गये। एस०के० राय के पास उस समय २६ प्रतिशत शेयर बचे थे। उस समय कोई भी नहीं समझ सका था कि भविष्य में पारसमल लोढ़ा को इतना महत्व मिलेगा।

उस समय संस्था की आर्थिक पूंजी ८०० करोड़ रुपए थी। पारसमल लोढ़ा भी समझ रहे थे कि यदि मैं अपने प्रभाव का उपयोग कर ८०० करोड़ की पूंजी पर नियंत्रण पा जाऊं, तो क्या बुरा है।

३० अक्तूबर, १९८६ को पारसमल लोढ़ा ने स्वयं पीयरलेस का संचालन शुरू किया और खुलकर पीयरलेस पर कब्जा जमाने की लड़ाई में उतर आये। उसी दिन उन्होंने पीयरलेस संचालक के रूप में कार्यभार संभाला। फिर छह महीने बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश से निक्को को पीछे हटना पड़ा। इधर छह महीने की इस अवधि में बहुत से इक्वीटी शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गये। डाइरेक्टर बोर्ड में भी व्यापक फेरबदल हुआ। निक्को का कहना था कि पीयरलेस में शामिल होने पर टकराव हो सकता है। यह भी बताया जाता है कि पारसमल लोढ़ा से इसी मामले में उसका शीतयुद्ध शुरू हो गया। दिल्ली में अरुण नेहरू का पतन होने पर निक्को बड़ी परेशानी में फंस गया। इसके अलावा और भी कई कारणों से दोनों पक्षों के बीच कटुता पैदा हो गयी।

अपने अनेक लोगों को पीयरलेस में शामिल कराकर पारसमल लोढ़ा ने उस प्रतिष्ठान पर कब्जा किया। इनमे पी०सी० सेन प्रमुख हैं। पी०सी० सेन इसके पहले भ्रष्ट आचरण के आरोप में बर्न स्टैंडर्ड से निष्कासित हुए थे। पीयरलेस बोर्ड ने पारसमल के साथ संयुक्त रूप से पी०सी० सेन पर सारे महत्वपूर्ण काम का भार सौंप दिया। इसके अलावा बर्न स्टैंडर्ड के एक अन्य व्यक्ति को भी पीयरलेस में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया।

निक्को ग्रुप से सबसे पहले पी०सी० सेन का मनमुटाव हुआ। इसके अलावा निक्को ग्रुप ने पीयरलेस के बारे में जो कुछ सोचा था, वह नहीं हो सका। दूसरी तरफ विभिन्न कारणों से पारसमल लोढ़ा का निक्को ग्रुप से तनाव बढ़ता जा रहा था। अंत में निक्को ने सारे शेयर बेच दिये। पारसमल के पास उस समय पीयरलेस के २० प्रतिशत शेयर थे और उनके मित्र तुहिन बाबू के पास भी उतने ही शेयर थे। फलस्वरूप इन दोनों की सम्मिलित शक्ति के आगे एस०के० राय की शक्ति क्षीण पड़ गयी। लेकिन मजे की बात यह है कि पारसमल और तुहिन बाबू बराबर बराबर शेयरों के मालिक थे, फिर भी पारसमल की चर्चा अधिक होने लगी। अनुमान है कि बिड़ला ग्रुप के नजदीकी आदमी होने कारण पारसमल के संदर्भ से पीयरलेस ने अनेक प्रतिष्ठानों को रुपए उधार दिये। वे सब पारसमल पर इतना निर्भर रहने लगे कि पीयरलेस में उनकी छवि स्वाभाविक रूप से सर्वोपरि हो गयी।

जानकार सूत्रों का कहना है कि पारसमल लोढ़ा को यह सफलता तुहिनकांति घोष व पी०सी० सेन के कारण मिली। पारसमल के पीयरलेस अभियान में इन दो लोगों ने बराबर उनकी सहायता की। इस कारण आगे आने में पारसमल को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

पारसमल लोढ़ा की पीयरलेस विजय को लेकर बहुतों के मन में अनेक सवाल उठे। पहला यह कि निक्को ने जो शेयर बेचे, उन्हें एस०के० राय ने अकेले ही क्यों नहीं खरीद लिया ? जानकार सूत्रों का कहना है कि पीयरलेस पर अधिकार जमाने के मामले में पारसमल अनेक बार एस०के० राय के पास विचार-विमर्श हेतु गये थे। संभवतः तभी राय साहब ने पारसमल को अपने मन की बात बता दी थी। पारसमल ने उसी का फायदा उठाया।

पीयरलेस की जमाराशि बढ़ाकर पारसमल लोढ़ा ने अपनी छवि बनानी शुरू कर दी। उनके लिए अपने स्वप्न को साकार करने का रास्ता खुल गया था। अभी हाल में पीयरलेस ने देश के चार बैंकों को प्रीमियम लेने के लिए अधिकृत किया है। पिछले साल स्टेट बैंक से ही अन्य बैंकों को लगभग १० करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। इस समय ८०० करोड़ रुपए पारसमल लोढ़ा के नियंत्रण में हैं। इसी के साथ वह पीयरलेस से जुड़े ढाई करोड़ मध्यमवर्गीय लोगों के भाग्य विधाता भी हैं। देखना है पीयरलेस के नये सर्वेसर्वा पारसमल लोढ़ा कठिन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में कितनी देर तक टिक पाते हैं ?

—विशेष प्रतिनिधि

वरदराजन

एक माफिया डान का अंत

बंबई माफिया जगत के प्रमुख स्तंभ वरदराजन उर्फ वरदा भाई को सिर्फ अपराध जगत ही अपना इष्टदेव नहीं मानता था, बल्कि राजनीतिज्ञों को चुनाव जीतने के लिए उसकी कृपा-दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था। अवैध शराब के धंधे का बेताज बादशाह वरदा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम०जी० रामचंद्रन को अपना दोस्त मानता था और श्रीलंका के विद्रोही तमिलों को हथियार और धन से सहायता करता था। उसकी मौत पर उसके विशाल इलाके में जिस तरह शोक मनाया गया, वह सम्मान विरलों को ही नसीब हो पाता है...

वरदा (इनसेट) की शोक संतप्त पत्नी

पिछले तीन दशक से बंबई में अवैध शराब के एकछत्र डान और अपराधियों के मसीहा ६० वर्षीय वरदा भाई के नाम से लोकप्रिय वरदराजन मुदालियार की २ जनवरी '८७ को मद्रास में दिल के दौरे से हुई मौत के फलस्वरूप बंबई के माफिया डानों का एक महत्वपूर्ण कीर्ति स्तंभ चरमरा गया। उसकी मौत की खबर मिलते ही एशिया की सबसे बडी झोंपड़पट्टी धरावी, शीवं-कोलीवाड़ा, माटुंगा, एंटाप हिल तथा आसपास के लगभग १५ लाख की आबादीवाले क्षेत्र में मातम छा गया और बाकायदे तीन दिन का शोक मनाया गया। न दूकानें खुलीं न मनोरंजन कार्य हुए। हाजी मस्तान तथा वरदा भाई के सहयोगियों ने उसका शव मद्रास से बंबई ले आने के लिए इंडियन एयरलाइंस का १४० सीटोंवाला एक विमान चार्टर किया। हाजी मस्तान अंत तक उसके शव के साथ रहा। उसकी विशाल शव यात्रा निकाल कर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

अपराध जगत के अलावा बंबई के दक्षिण भारतीय भी उसे भगवान जैसा ही मानते थे, क्योंकि डेढ़ दशक तक शिवसेना और दक्षिण भारतीयों के बीच चलनेवाले तनाव तथा शिवसैनिकों के खौफ को वरदराजन ने ही खतम कर बंबई के दक्षिण भारतीयों को बेखौफ बनाया था, साथ ही दक्षिण भारतीय बहुल इलाके माटुंगा स्टेशन पर विशाल स्तर पर हर वर्ष गणेशोत्सव का आयोजन कर महाराष्ट्रीयों को भी अपने पक्ष में कर लिया। पुलिस ने इस गणेशोत्सव को रोकने या कहीं और स्थानांतरित कर वरदा भाई के प्रभाव को नाकाम करने की हरचंद कोशिश की, लेकिन अपने व्यापक जनसमर्थन का फायदा उठाकर वरदा भाई ने पुलिस को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया।

आंख मिचौली का खेल: बंबई पुलिस और वरदा भाई के बीच आंख मिचौली का खेल लगभग दो दशक पुराना है, लेकिन उसे बल मिला माटुंगा सायन क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आये उप पुलिस आयुक्त वाई०सी० पवार के कारण, जिन्होंने वरदा भाई के एकछत्र साम्राज्य को तोड़ने का संकल्प किया था और उसके अड्डों पर छापा मारने का अभियान आंधी की तरह शुरू कर दिया। अपराध के अजेय गढ़ धरावी, एंटाप हिल तथा शीवं-कोलीवाड़ा में बननेवाली अवैध शराब की सप्लाई अधिकांश बंबई तथा बंबई से बाहर भी होती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में अनधिकृत जुए तथा बार थे, जिनके बाहर सोशल क्लब का बोर्ड लगा होता था। ऐसे अड्डों को सोशल क्लब के बोर्ड तले चलाने की परंपरा वरदा भाई ने ही शुरू की थी, जहां आनेवाले ग्राहकों-जुएबाजों के मनोरंजन के लिए वेश्याएं भी रहती थीं। हाजी मस्तान तथा उसके गिरोह द्वारा स्व० जयप्रकाश नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद तस्करी का केंद्र वरदा भाई के इलाके में व्यवस्थित हो गया। वरदा भाई के इस बढ़ते प्रभाव को तोड़ने की हाजी मस्तान, सुकुर नारायण बखिया, करीम लाला, यूसुफ पटेल जैसे माफिया डानों ने भी काफी कोशिश की—बहुत सारी हिंसात्मक वारदातें भी हुईं, लेकिन वरदा भाई का प्रभाव बढ़ता ही गया।

उप आयुक्त वाई०सी० पवार ने जब सीधे वरदा भाई के अड्डों पर छापा मारना शुरू किया, तो पुलिस और वरदा भाई के गिरोह की आंख मिचौली का खेल आमने-सामने जंग के रूप में परिणत हो गया। वाई०सी० पवार उसे गिरफ्तार कर, अदालत से लंबी सजा दिलाकर, उसके आपराधिक जीवन पर खातमे की मुहर लगा देना चाहते थे, लेकिन चतुर, अपराधकुशल वरदा कभी भी अपने जुर्म का न कोई सबूत छोड़ता था और न ही कोई उसके विरुद्ध सबूत या गवाही देने के लिए तैयार होता था। कोई भी अड्डा उसके नाम से नहीं चलता था, न ही किसी पर उसका कागजी मालिकाना हक था। तेलंग रोड, माटुंगा स्थित 'वसुधा' के मामूली फ्लैट में कुबेरपति वरदा अपने परिवार के साथ रहता था, जहां कायदे के फर्नीचर भी नहीं थे। वह हमेशा टैक्सी से चलता था। अपने लंबे आपराधिक जीवन में वह सिर्फ दो बार गिरफ्तार और दो बार नजरबंद हुआ था। पहली बार १९६४ में अपने ही गिरोह के एक सदस्य लंबू मट्टू की हत्या के आरोप में, दूसरी बार १९८५ में एक व्यक्ति को धमकाने के आरोप में। १९८४ और १९८५ में कोफेपोसा (१८ महीने के लिए) तथा रासुका के तहत नजरबंद हुआ, लेकिन रासुका से सलाहकार बोर्ड ने उसे रिहाई की अनुमति दे दी।

टेप कांड: वरदा प्रचार और सुर्खियों से अलग हट कर काम करता था, इसीलिए हाजी मस्तान से लेकर यूसुफ पटेल जैसे तस्करों की तरह उसका नाम सुर्खियों में नहीं आने पाया और अधिकांश बंबईवासी उसके नाम से तब तक अपरिचित रहे जब तक उसका 'टेप-कांड' चर्चा में नहीं आया। अपने विरुद्ध पुलिस थानों में दर्ज मामलों तथा पुलिस की दखलंदाजी को रोकने के लिए उसने माटुंगा थाने के दो पुलिस अधिकारियों

(देशमुख तथा सैम्सन) से हुई अपनी बातचीत को टेप कर उसे उजागर कर दिया जिसके फलस्वरूप इन दोनों पुलिस अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया।

दरअसल, वरदा भाई की यह एक चाल थी— वाई०सी० पवार के कैरियर को फिल्मी ढंग से खतम करने की। लेकिन यह टेप-कांड वरदा के एकछत्र साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया और वहां की पुलिस उसके विरुद्ध हो गयी और हर जगह नाकेबंदी शुरू कर दिया। माटुंगा में जिस तरह वह १० दिनों तक विशालकाय पंडाल लगाकर गणपति-पूजा का आयोजन कराता और फिल्मी कलाकारों, राजनीतिज्ञों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करता, वहां पर पूजा आयोजन करने की अनुमति पुलिस ने न केवल रद्द कर दी, बल्कि ठीक उसी स्थल पर एक पुलिस चौकी भी कायम कर दी। १९८५ में वरदा ने अदालत की शरण लेकर अनुमति ले ली, लेकिन पंडाल का आकार छोटा हो गया।

कुलीगीरी से शुरुआत : लगभग चार दशक पहले मद्रास में मुफलिसी की जिंदगी बिता रहा वरदराजन काम की तलाश में बंबई आया और बंबई बंदरगाह पर कुलीगीरी शुरू कर पेट पालने लगा। हाजी मस्तान ने भी यहीं से कुलीगीरी कर अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी, वरदा भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चला और बंदरगाह पर चोरी जैसे मामूली जुर्म से शुरू कर सोने-चांदी की तस्करी में लिप्त हो गया। हाजी मस्तान सोने की और यूसुफ पटेल चांदी की तस्करी का जब बादशाह बन गया, तो वरदा की उन दोनों से सीधे ठनने लगी, लेकिन इसमें अपना ही नुकसान देख वरदा ने अपने लिए तस्करी का एक नया रास्ता चुन लिया— शराब की तस्करी का। उस समय बंबई में दारूबंदी होने के कारण वरदा की चांदी हो गयी। उसने अपने लिए एंटाप हिल से शीवं-कोलीवाड़ा का निषिद्ध क्षेत्र चुना, जहां पुलिस फटकती नहीं थी और न ही वहां पुलिस स्टेशन थे। उसने झोंपड़पट्टीबहुल इस इलाके में अवैध शराब के तमाम अड्डे बना दिये। इस क्षेत्र में अधिकांश आबादी दक्षिण भारत से काम की तलाश में आये गरीबों की थी, वरदा ने उन्हें रोजगार और आर्थिक सहायता के साथ-साथ संरक्षण देना शुरू किया जिसके फलस्वरूप वह बड़े आराम से पुलिस और कानून की निगाहों से दूर रहकर अपने कारोबार को बढ़ाता रहा।

वरदा को महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु से भी राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। एम०जी० आर० से उसके घनिष्ठ संबंध बन गये थे। एक बार पुलिस ने समूची बंबई में आधी रात को अचानक छापे मारकर सभी छोटे-बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिर्फ वरदा ही उनकी चंगुल में नहीं फंसा। उसे छापे की अपने विशेष संपर्क-सूत्र से खबर मिल गयी और वह भूमिगत हो गया। पुलिस उसकी तलाश में समूची बंबई छानती रही, लेकिन उसकी झलक तक नहीं पा सकी।

पिछले वर्ष पुलिस द्वारा गैरजमानती वारंट तामील किये जाने पर वरदा बंबई से फरार हो मद्रास चला गया, जहां राजनीतिक संरक्षण के कारण बंबई पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकी। वह उसे गिरफ्तार कर बंबई से बाहर कराना चाहती थी, लेकिन बंबई उच्च न्यायालय में, इस कार्रवाई को वरदा ने चुनौती देकर पुलिस को निष्क्रिय कर दिया। यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। वरदा अपना वारंट रद्द कराकर बंबई लौटना चाहता था और पुलिस के निरंतर छापों के कारण छिन्न—भिन्न हो रहे अपने अवैध शराब के धंधे को पुनः सुव्यवस्थित करना चाहता था लेकिन वाई०सी० पवार के कारण संभव नहीं था। अतएव उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का फायदा उठाकर उपआयुक्त वाई०सी० पवार का बंबई से ही स्थानांतरण करा दिया। तत्कालीन पुलिस आयुक्त (अब महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक) दत्तात्रेय सोम ने उसके स्थानांतरण को रोकने और टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेपों के सामने उनकी एक न चली।

फिल्मों का मसाला : वरदा जब बंबई में था तब यहां से, फिर मद्रास पहुंच कर वहां से श्रीलंका में तमिल उग्रवादियों को हथियारों और धन से पूरी तरह से सहायता करता रहा। उसके अंतिम दिनों में मद्रास के एक फिल्म निर्माता ने वरदा की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म 'नायकम' बनायी थी, जिसमें कमल हसन ने वरदा की भूमिका निभायी थी। 'नायकम' ने बाक्स आफिस पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के पिछले एक दशक का सफलता का कीर्तिमान तोड़ दिया था। अब इसका री-मेक कन्नड़, मलयालम तथा तेलगू सहित हिंदी में भी हो रहा है। हिंदी री-मेक में वरदा की भूमिका विनोद खन्ना निभा रहे हैं। यों पांच वर्ष पहले गोविंद निहलानी ने 'अर्द्धसत्य' में वरदा के चरित्र को रामा शेट्टी के रूप में पेश किया था और यह भूमिका निभाकर सदाशिव अम्रापुरकर स्टार बन गये। 'अर्द्धसत्य' बाक्स आफिस पर उसी तरह हिट रही थी, जिस तरह हाजी मस्तान की जिंदगी पर आधारित 'दीवार' जिसके बाद अमिताभ बच्चन सुपर स्टार का ओहदा पा गये थे। यही आशा अब विनोद खन्ना कर रहे हैं 'नायकम' के हिंदी री-मेक में काम कर।

वरदा सिर्फ एक माफिया डान नहीं था, उसकी मर्जी के बगैर उसके क्षेत्र में पत्ता तक नहीं हिलता था। अ०भा० युवक कांग्रेस के अध्यक्ष गुरुदास कामत, महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री बी० सुब्रह्मण्यम, प्रथम पंक्ति के नेता शरद दिघे आदि पर वरदा का वरदहस्त माना जाता था और वसंत दादा पाटील को जिताने में भी उसकी काफी भूमिका थी। वर्षों पहले राजीव गांधी के सम्मान में दिये गये भोज की व्यवस्था वरदा ने ही की थी और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया था। माटुंगा-शीवं क्षेत्र में बस्ती का नाम वरदराजन नगर रखा गया था। और वरदा बड़े फख्र से कहा करता था कि 'यहां अफसर आते हैं, जाते हैं, लेकिन वरदा भाई का काम निर्द्वन्द्व चलता रहता है।' और यह बात उसने साबित भी कर दिखायी थी।

—रवींद्र श्रीवास्तव

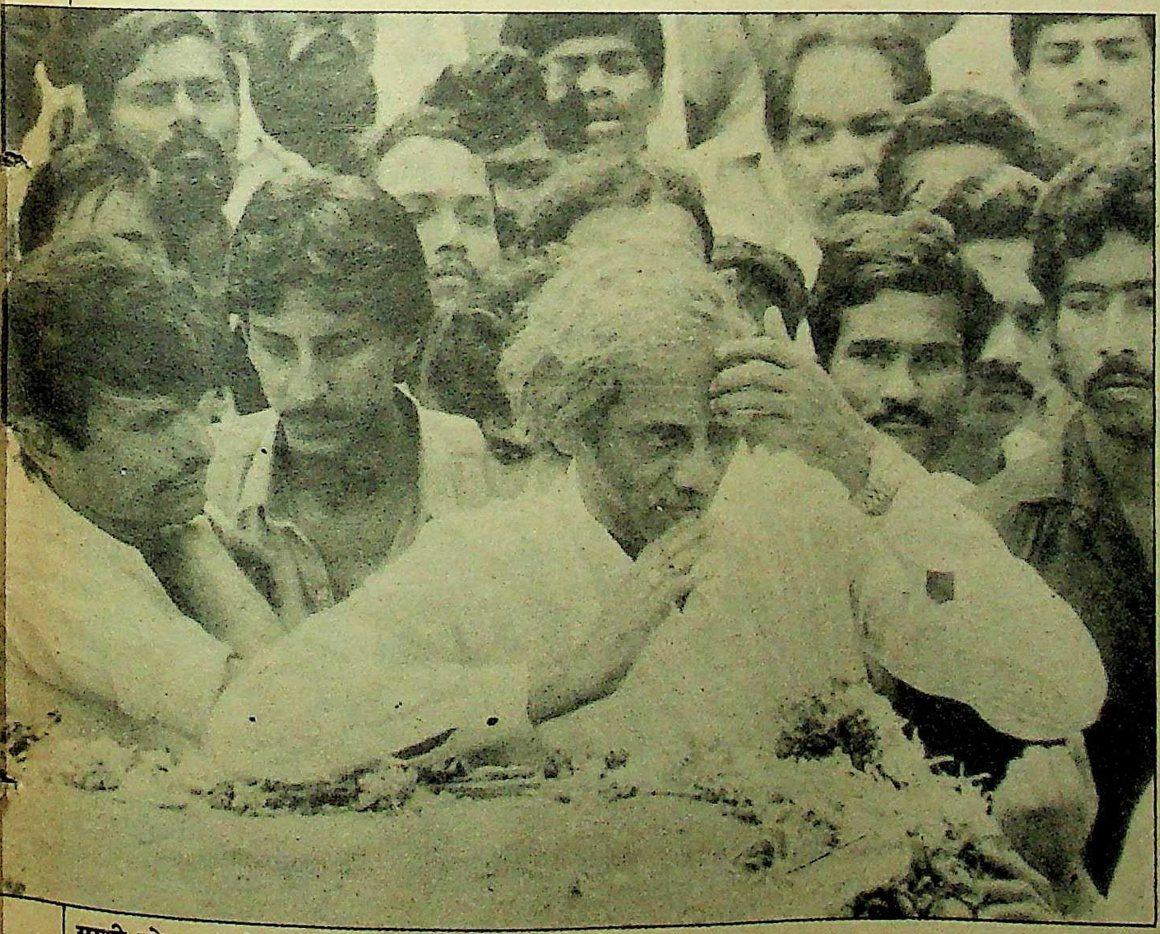

साथी को श्रद्धांजलि : हाजी मस्तान वरदराजन की शवयात्रा के समय

जिंबाब्वे

समाजवाद की ओर

अफ्रीकी देश जिंबाब्वे में एक नाटकीय घटना घटी है। सत्तारूढ़ पार्टी जानू (जिंबाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन) और विपक्षी पार्टी जापू (जिंबाब्वे अफ्रीकन पीपुल्स यूनियन) ने आपस में विलय करके देश में एकदलीय शासन पद्धति लागू करने की शुरुआत कर दी है। विलय के बाद की गयी घोषणा के अनुसार इस शासन पद्धति के जरिये मार्क्सवादी-लेनिनवादी कार्यक्रम के तहत देश में समाजवाद लाया जायेगा।

एक लंबे अरसे से विपक्षी पार्टी 'जापू' ने 'जानू' के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। 'जानू' ने कई बार यह आरोप भी लगाया था कि 'जापू' आंदोलन में हिंसक तरीके भी अपना रही है, मगर 'जापू' नेता जोशुओ अंकोमो इस आरोप से इनकार करते थे, यद्यपि दोनों पार्टियों के बीच की यह लड़ाई केवल सात साल पुरानी थी। रोडेशिया (जिंबाब्वे) को इयान स्मिथ की गोरी सरकार से आजाद करवाने के लिए अंकोमो और राबर्ट मुगाबे ने संयुक्त रूप से प्रयास किये थे। १९८० में जिबाब्वे स्वतंत्र हुआ, तो मुगाबे पहले प्रधानमंत्री बने और अंकोमो को उन्होंने अपना गृहमंत्री बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद मुगाबे को शक हुआ कि अंकोमो उनका तख्ता उलटने के प्रयास में सलग्न हैं, तो उन्हें और उनके साथियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अंकोमो ने भागकर ब्रिटेन में शरण ले ली और 'जापू' पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ समय के बाद अंकोमो जिबाब्वे लौट आये। मुगाबे ने भी बीच का रास्ता अपनाना तय किया। असल में इस विलय की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। पिछले साल के मध्य में गोरों के लिए चुनाव में आरक्षित सीटों का नियम खतम करने का मकसद भी यही था।

दोनों ही नेताओं ने इस विलय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है, "जिबाब्वे को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक जरूरी कदम है।" अफ्रीकी देशों में, जहां से आये दिन सत्ता उलटने के समाचार सुनने को मिलते हैं, ज़िबाब्वे यदि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब जिबाब्वे की नयी व्यवस्था में प्रधानमंत्री मुगाबे ने राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। अंकोमो को द्वितीय उपराष्ट्रपति का पद सौंपा गया है।

यद्यपि ये आरोप लगाये जा रहे हैं कि मुगाबे द्वारा एक दलीय शासन पद्धति लागू करने की वजह सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना रहा है, मगर यह बात नहीं कही जा सकती कि केवल इसी खातिर उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है। मुगाबे और अंकोमो दोनों नेता समाजवादी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुगाबे चीन की साम्यवादी क्रांति से अभिभूत थे, तो अंकोमो सोवियत क्रांति को अपना आदर्श मानते थे।

सवाल यह उठता है कि इस नये परिवर्तन से जिंबाब्वे को क्या लाभ होगा? असल में पश्चिमी पैटर्न की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस पर विदेशी कर्ज बहुत बढ़ चला था। मुद्रास्फीति भी बढ़ गयी थी। बेरोजगारों की संख्या में भी इजाफा हो रहा था। पश्चिमी देश जिंबाब्वे से कच्चा माल आयात करके मुनाफा कमा रहे थे और अन्य अविकसित राष्ट्रों की भांति जिंबाब्वे की भी कमर टूट रही थी। निस्संदेह इस नयी व्यवस्था से तुरंत उसे कोई लाभ नहीं होगा। पूंजीपति अब वहां पूंजी निवेश नहीं करेंगे और सहायता के लिए अब उसे केवल समाजवादी देशों की तरफ देखना पड़ेगा। मगर खास बात यह है कि अब वह किसी बड़े राष्ट्र के शोषण का शिकार नहीं होगा और जो भी तरक्की करेगा, अपने संसाधनों के दम पर।

अफगानिस्तान

समाधान के संकेत

अफगानिस्तान इस समय अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाया है। इसका कारण यह है कि वहां दो घटनाएं साथ-साथ और बड़ी तेजी से घट रही हैं। एक तो पाकिस्तान-अफगान सीमा पर स्थित खोस्त शहर के पास अफगानी सेना और छापामारों में चल रहा भयंकर युद्ध और दूसरी मास्को से आ रही सकारात्मक घोषणाएं।

सोवियत संघ के विदेशमंत्री एदुंअर्द शेवर्दनात्जे की घोषणा के बाद लग रहा है कि शायद सन् १९८८ अफगानिस्तान समस्या के लिए 'समाधान का साल' साबित हो। अपनी हाल की काबुल यात्रा के बाद उन्होंने घोषणा की है कि रूस एक साल के अंदर अफगानिस्तान से अपनी फौज हटा लेने को तैयार है और यदि अमरीका छापामारों को सैनिक सहायता देना बंद कर दे, तो यह काम और भी कम समय में निपट सकता है। उधर विदेश मंत्री माइकल आर्माकोस्ट की इस्लामाबाद यात्रा के बाद अमरीका का नजरिया भी पहले की अपेक्षा कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है।

लगभग आठ साल पहले दिसंबर १९७९ में अफगान सरकार के बुलावे पर सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। रूसी सेना के प्रवेश के बाद अमरीका ने अफगान छापामारों को सैनिक प्रशिक्षण और अस्त्र-शस्त्र देना शुरू कर दिया, जिससे समस्या और उलझती गयी। इस समय लगभग एक लाख रूसी सैनिक अफगान सेना की मदद के लिए अफगानिस्तान में तैनात हैं।

यों तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि डिआगो कार्दोवेज की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह-सफायी की कोशिशें चलती रहीं, मगर कोई हल नहीं निकला। अप्रत्यक्ष वार्ताओं में केवल इतनी प्रगति हुई कि दोनों देश कुछ मुद्दों पर सहमत हो गये। इस दिशा में वास्तविक प्रगति मिखाइल गोर्बाचोव के सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने के बाद हुई। पहले तो बबरक करमाल की जगह डा० नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया, जिससे थोड़ा लचीला रवैया अपनाया जा सके। डा० नजीबुल्लाह ने छापामारों के सामने आम माफी और सत्ता में भागेदारी जैसे प्रस्ताव रखे, मगर इसमें आंशिक सफलता ही हाथ लग सकी। उधर दोनों महाशक्तियों के बीच हुए शिखर सम्मेलनों में भी अफगान समस्या प्रमुख मुद्दा बनी रही और हाल में मध्यम दूरी के समझौते के अवसर पर भी यह मुद्दा उठा था।

दूसरी तरफ खोस्त शहर के पास अफगानी सेना निर्णायक युद्ध लड़ रही है। खोस्त सैनिक महत्व का क्षेत्र है। १९७९ से ही इस पर छापामारों का कब्जा रहा है। अफगानिस्तान से जो रिपोर्टें आ रही

फौजियों से सलाह-मशविरा : डा० नजीबुल्लाह

हैं, उनके मुताबिक तो अफगानी सेना ने खोस्त पर अधिकार कर लिया है और ६० ट्रक रसद हाल में ही वहां पहुंचायी गयी है। अनुमान है कि इस लड़ाई में अभी तक १५०० छापामार और ३०० के आसपास सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि खोस्त पर कब्जा करने के बाद वार्ताओं में अफगान का पक्ष और मजबूत हो जायेगा।

मगर इन दो बातों से भी ज्यादा दिलचस्प है पाकिस्तान के सेना अधिकारियों में उपजा विवाद। कुछ पाक सैनिक अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि अफगान समस्या के सुलटने से अमरीकी इमदाद कम हो जायेगी, तो कुछ का सोचना है कि समाधान से अफगान शरणार्थियों की समस्या से निजात मिलेगी।

इस सबके बावजूद समाधान अभी दूर है। सोवियत सेना की वापसी के बाद लोकप्रिय सरकार का गठन करना भी कोई छोटी समस्या नहीं होगी। कम-से-कम अमरीका तो यह हरगिज नहीं चाहेगा कि वहां कोई रूस समर्थक सरकार बने।

बंगलादेश

इरशाद का धर्म संकट

चुनावों की घोषणा के बाद बंगलादेश की राजनीति बिलकुल अनिश्चित-सी लगने लगी है। एक तरफ राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद ने जिद पकड़ रखी है कि चुनाव तयशुदा तारीख यानी २८ फरवरी को जरूर होंगे, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार करने का अपना फैसला बरकरार रखा है।

१० नवंबर को विपक्षी दलों द्वारा शुरू किये गये 'इरशाद हटाओ' आंदोलन को दो माह से भी ज्यादा होने जा रहे हैं। ६ दिसंबर को जनरल इरशाद ने संसद भंग करने की घोषणा कर दी थी। बंगलादेश के संविधान के मुताबिक चुनाव तीन महीने के अंदर हो जाने चाहिए, इसलिए चुनाव की तारीख भी मुकर्रर कर दी गयी। इरशाद चाहते हैं कि उनका राष्ट्रपति पद बरकरार रहे और चुनाव के जरिये लोकतंत्र स्थापित हो जाये। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इरशाद के पद पर बने रहने से निष्पक्ष चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देकर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए, जिसकी देखरेख में चुनाव संपन्न हो सकें।

तीन प्रमुख विपक्षी पार्टियों (आवामी लीग, बंगलादेश नेशनल पार्टी और जमायते इस्लामी) ने न केवल चुनाव का बायकाट करने का, बल्कि चुनाव न होने देने का इरादा बना लिया लगता है। २० जनवरी को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है और इन दलों ने १७ जनवरी से २० जनवरी तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। उधर इरशाद ने ७६ छोटी-छोटी पार्टियों के नये गठबंधन को विपक्ष के रूप में खड़ा करने की कोशिश की है। इस नये मंच के अध्यक्ष बुताब्दुर रब ने कहा है, "चुनाव का विरोध करने की कोई भी कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाना होगा।" लेकिन यह गठबंधन बंगलादेश की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं रखता।

वैसे ये संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों को मनाने के लिए इरशाद कुछ और छूटें दे सकते हैं। मसलन, वह मौजूदा मंत्रिमंडल को भंग करने और चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की पेशकश कर सकते हैं, मगर इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि ये पार्टियां इरशाद के राष्ट्रपति पद से हटने की अपनी मांग को वापस लेंगी।

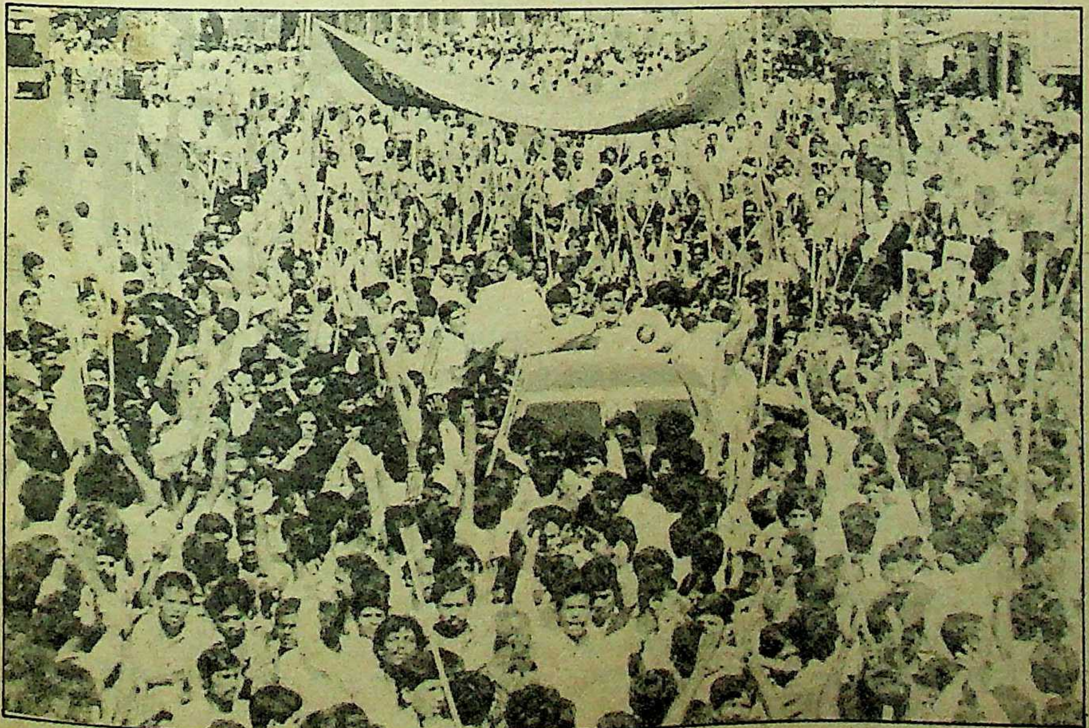

इस विरोध को कब तक रोक पायेंगे इरशाद ?

अमरीका

दोमुंही नीति

१६ दिसंबर, १९८७ को दोनो महाशक्तियों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते को यदि पहले आघात की तरह देखा जाये, तो गलत न होगा। रीगन और गोर्बाचोव के बीच हुए जिनेवा सम्मेलन में दोनों नेताओं ने रासायनिक शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया था, मगर हाल के अमरीकी फैसले से आशा धूमिल पड़ गयी है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से सोवियत संघ ने पहली बार अपने रासायनिक शस्त्रों की मात्रा की जानकारी दी है।

दरअसल, रासायनिक शस्त्रों के निर्माण के फैसले के पीछे एक दिलचस्प राजनीति है। मूलतः अमरीका 'हथियारों का व्यापारी' है। उसकी अर्थव्यवस्था हथियारों को बनाने और बेचने पर टिकी हुई है। इसीलिए मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर होने पर जहां पूरा विश्व तालियां पीट रहा था, तो बहुत से दक्षिणपंथी सीनेटर और उद्योगपति इस शांति समझौते के विरोध में नारे लगा रहे थे। इनका विरोध मूलतः इसी बात पर आधारित था कि यदि शांति आ गयी, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। इतिहास में नाम लिखाने की हुलहुली में रीगन ने समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिये, मगर फिर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था और रिपब्लिकन पार्टी के शुभचिंतकों को खुश रखने की चिंता सताने लगी। सो उन्होंने सीनेटरों और व्यापारियों को समझाया, "भई घबराते क्यो हो। प्रोडक्ट बदल दो। अभी तक प्रक्षेपास्त्र बनाते थे, अब रासायनिक अस्त्र बनाओ। इससे हमारी शांतिदूत की छवि भी बनेगी और तुम्हारा हथियारों का धंधा भी जोरों से चलेगा।"

रासायनिक हथियार बहुत घातक होते हैं। इनसे लोग मरते तो हैं ही, लेकिन इससे भी भयावह यह बात है कि बचे लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। शारीरिक अपंगता, मानसिक विक्षिप्तता के अलावा इन शस्त्रों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग पर रोक लगाने की दिशा में १९२५ में जिनेवा संधि हुई थी। इससे दूसरे युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग बहुत कम हुआ। हालांकि इस रोक के बावजूद मुसोलिनी की सेना ने रबिसीनिया में तथा जापानियों ने मंचूरिया में रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वियतनाम युद्ध में (१९६३) अमरीका ने इन शस्त्रों का जमकर प्रयोग किया था, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पर्याप्त भर्त्सना भी हुई थी। उसने शरणार्थी शिविरों पर ट्राइकोथिसीन और माइकोटाक्सीन (पीत वर्षा) का प्रयोग किया था।

इस समय १५ से भी ज्यादा देशों के पास रासायनिक हथियार हैं। अमरीका के इस निर्णय के बाद यह दौड़ और तेज हो जायेगी।

—मुकेश कुमार

राजू भटनागर

मुठभेड़ की असलियत

लखनऊ से आये विशेष पुलिस दस्ते ने एस०पी० सिटी (लखनऊ) एस०एन० सिंह के नेतृत्व में दस जनवरी को इलाहाबाद में दिनदहाड़े कुख्यात अपराधी राजू भटनागर को गोलियों से छलनी कर देने का दावा किया है, लेकिन गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित इस बात की आई०जी० स्तर पर जांच क्यों करा रहे हैं कि राजू भटनागर किसकी गोली से मरा? क्या राजू को उसी के किसी साथी से मरवाया गया है? ऊंचे राजनीतिक संरक्षणदाताओं के कारण जिसके लिए तिहाड़ जेल से खुद फरार होना और अंतरराष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स शोभराज को वहां से फरार करा देना इतना सरल था, तो उस राजू भटनागर ने पुलिस के सामने समर्पण करने के बजाय मुठभेड़ का रास्ता क्यों अपनाया? राजू की मौत के बाद खानातलाशी में पुलिस को कार से गोलियों के २१ खोल और ९ जीवित कारतूस मिले हैं। क्या राजू ने २१ गोलियां चलायी थीं— लेकिन उनसे कोई पुलिसकर्मी घायल क्यों नहीं हुआ? क्या ऊंचे पदों पर आसीन कुछ शक्तिशाली लोग अपना भांडा फूटने के भय से यह नहीं चाहते थे कि राजू भटनागर जीवित पकड़ा जाये? राजू भटनागर किस तरह का अपराधी था? वह इलाहाबाद क्यों आया था? और उन क्षणों में वास्तव में क्या हुआ था, जिन क्षणों में लखनऊ पुलिस राजू भटनागर को मार डालने का दावा कर रही है?— माया की विशेष खोजबीन:

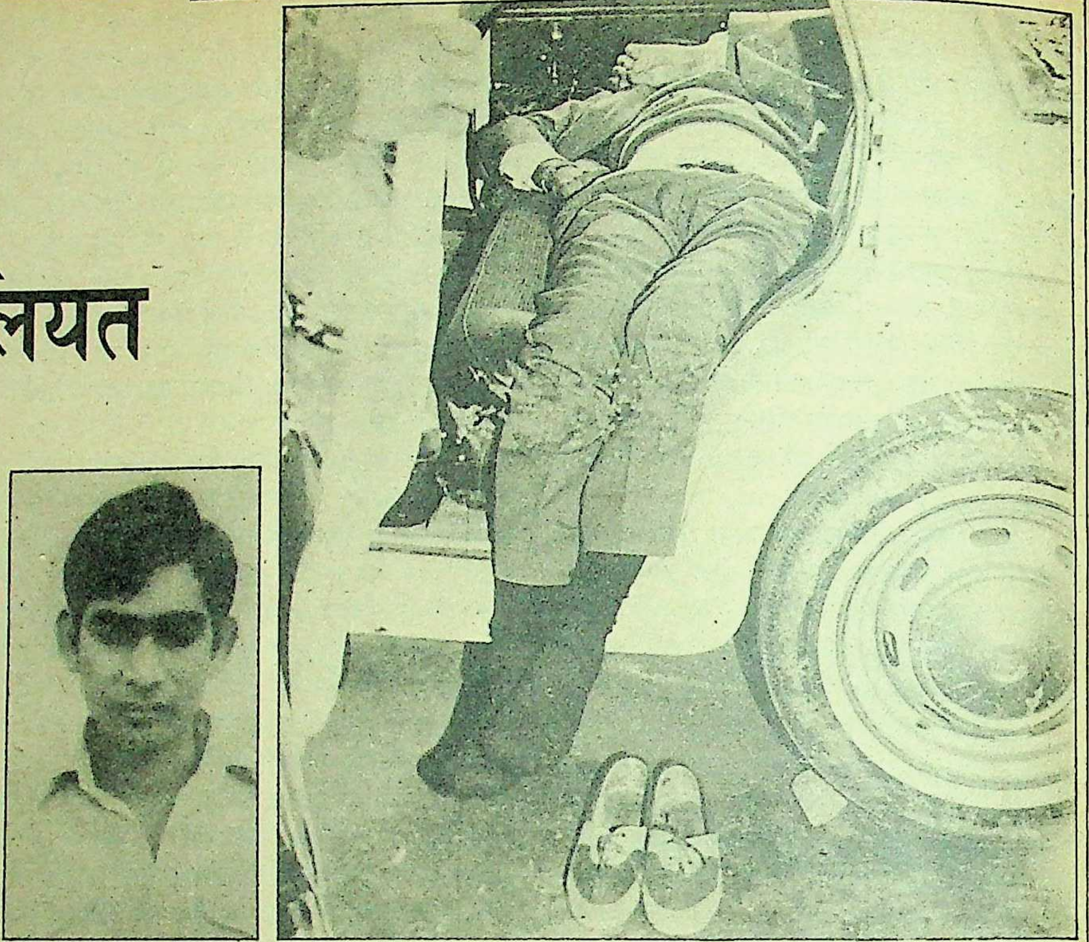

रहस्यमय पुलिस मुठभेड़: राजू भटनागर (बायें) और कथित मुठभेड़ के बाद उसका शव

छाया: विभुगुप्त

दस जनवरी को दोपहर बारह और दो बजे के बीच अफवाह की तरह यह खबर पूरे इलाहाबाद शहर में फैल गयी कि तिहाड़ जेल से फर्जी जमानत पर फरार होने और अंतरराष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स शोभराज को फरार कराने में मदद करनेवाला कुख्यात अपराधी राजू भटनागर लाउदर रोड के एक मोटर गैरेज में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और उसके दो साथियों—ओमप्रकाश उर्फ बबलू और ब्रजमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू की लाश को देखने के लिए मोटर गैरेज में भीड़ जुटने लगी। सफेद रंग की फियेट कार (नं०-यू०जी०के० ८२८०) की पिछली सीट पर राजू भटनागर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी छाती पर खून के निशान थे। कार के पीछे का शीशा टूटा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि यहां कुछ देर पहले गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार हुई है। वर्दीधारी पुलिस बाकायदा लाइन लगवाकर भीड़ को राजू भटनागर का शव दिखा रही थी और सबको घोषणापूर्वक बता भी रही थी कि 'इसे एस०पी० (सिटी) लखनऊ एस०एन० सिंह ने मारा' है।

राठ (हमीरपुर, उ०प्र०) का मूल निवासी राजू भटनागर इनामी अपराधी था। अनेक हत्याओं, बैंक-डकैतियों और अपहरण-कांडों के लिए अनेक राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। १९७६ से वह पुलिस के लिए एक आतंक बन चुका था। अनेक बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन ऊंची पहुंच के कारण हर बार फरार होता रहा। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने और पकड़वानेवाले को एक लाख रुपए से अधिक का इनाम देने की घोषणा अनेक राज्यों की पुलिस कर चुकी थी। राजू भटनागर की मौत की खबर लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंचते ही उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजनाथ गुप्त ने लखनऊ इलाहाबाद और कानपुर पुलिस को पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी। वस्तुतः राजू भटनागर की हत्या के साथ ही उसके सारे गैंग का सफाया भी हो गया था। कानपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद में उसके गिरोह के ११ सदस्यों में से सात सदस्य पुलिस की पकड़ में आ चुके थे। इन तीनों शहरों की पुलिस को पुरस्कृत करने की पुलिस महानिदेशक की घोषणा राजू भटनागर के सिर पर लगी इनाम राशि से अलग थी। इसलिए राजू की मौत के बाद सरकारी हलकों में लाखों रुपए की कीमत का जो पहला और अंतिम सवाल उठ खड़ा हुआ है, वह है— 'राजू भटनागर किसकी गोली से मरा है?'— घटनास्थल पर खुद सादी वर्दी में एस०पी० सिटी लखनऊ एस०एन० सिंह मौजूद थे, उपस्थित पुलिसकर्मी उनकी ही जय-जयकार कर रहे थे। पत्रकारों से उन्होंने खुद मुठभेड़ का पूरा खाका खींचते हुए बताया कि किस तरह सबसे पहले वह कार के दरवाजे तक पहुंचे थे, उन्होंने दरवाजा खोलनें की कोशिश की और राजू भटनागर को यह कहते हुए समर्पण करने का आदेश दिया कि 'राजू, तुम्हारा खेल खतम हो चुका है।' उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार राजू भटनागर द्वारा चलायी दो गोलियों से उन्होंने झुककर अपना बचाव किया और कार का दरवाजा न खुलने पर किस प्रकार साहसपूर्वक खिड़की से अपने रिवाल्वर की अनेक गोलियां राजू भटनागर के जिस्म में उतार दीं!— इतने स्पष्ट विवरण के बावजूद खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस विवरण को पूर्णसत्य मानने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित को आई०जी० स्तर पर 'राजू किसकी गोली

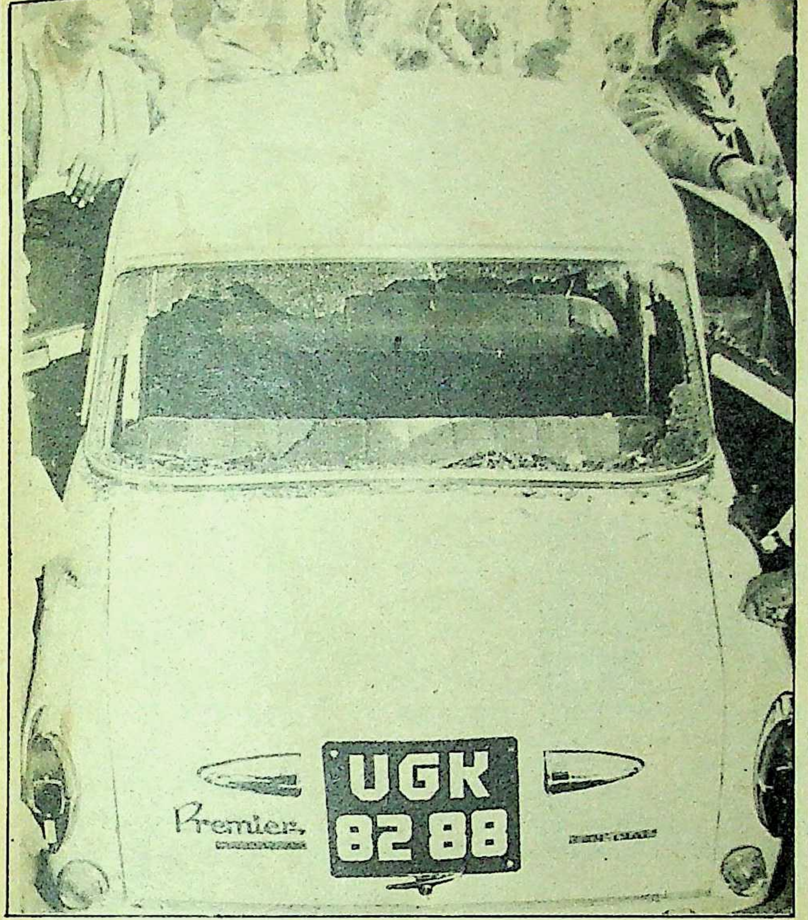

गोलियां किसने मारीं ? : क्षतिग्रस्त फियेट कार

ओमप्रकाश उर्फ बबलू

ब्रजमोहन शर्मा

से मरा ?' की जांच कराने की घोषणा न करनी पड़ती। राजू की गोलियों से छलनी लाश के प्रत्यक्ष दर्शक भी मुठभेड़ के सारे चिह्नों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी 'मुठभेड़' को पूर्ण सच नहीं मान रहे थेउत्तर प्रदेश सरकार के उक्त जांच आदेश ने भी 'मुठभेड़ की असलियत' पर लगे प्रश्न चिह्न पर अपनी मुहर लगा दी है। आखिर, यह गुत्थी क्यों उलझी ?

संदेह क कारण : हत्या, लूट व अपहरण के पचास से अधिक सनसनीखेज मामलों में वांछित राजू भटनागर ऊंची पहुंचवाला दिलेर, हंसमुख लेकिन क्रूर शहरी डकैत था। बैंक लूटना और रईस खानदान के लोगों का अपहरण करके लाखों की फिरौती वसूलना उसके प्रिय अपराध थे और शराब और शबाब के साथ हर तरह से मस्त जीवन जीना उसकी जिंदगी थी। वह बीहड़ों के डकैतों की तरह पुलिस से मोर्चा नहीं लेता था, बल्कि अपने संरक्षणदाताओं के कारण गिरफ्तार होकर फरार होने में माहिर था। बताया जाता है कि समर्पण के पूर्व चंबल के बागी मलखान सिंह ने राजू भटनागर को बीहड़ों में आने की दावत दी थी, लेकिन राजू भटनागर राजी नहीं हुआ। चार्ल्स शोभराज उसका आदर्श था। पहले जब भी वह पुलिस के सामने पड़ा— उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की और चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। १० जून, १९८१ को दिल्ली की पॉश कालोनी ईस्ट आफ कैलाश में जब वह पुलिस से घिर गया था, तो उसने बिना किसी हीलाहवाली के यह कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया था कि 'राजू तुम्हारा खेल अब समाप्त हो गया।' अत: यह बात किसी के गले आसानी से नहीं उतरती कि एस०पी० सिटी लखनऊ द्वारा दी गयी समर्पण की चेतावनी का जवाब राजू भटनागर ने गोलियों से दिया होगा।

पुलिस ने फियेट कार की तलाशी में ४ हजार रुपये के अलावा दो रिवाल्वरों की बरामदगी दिखायी है। एक०३२ बोर-१ मेक-४ ए ६२६६७ बाई बेबले एण्ड स्काट जिसमें चली हुई गोलियों के छह खाली खोल थे। दूसरी—०४५५ बोर की कोल्ट रिवाल्वर नं० ए-११९६१४९ जिसमें तीन खाली खोल और तीन जीवित कारतूस थे। इसके अलावा छह खाली खोल ४५५ बोर के और छह खाली खोल ३२ बोर के कार से मिले। राजू की जेब से भी छह जीवित कारतूस मिले। इस प्रकार पुलिस ने उस फियेट कार से गोलियों के २१ खाली खोल और ९ जीवित कारतूस बरामद किये हैं। क्या राजू भटनागर ने २१ गोलियां चलायी थीं ? लेकिन एक भी पुलिसकर्मी घायल क्यों नहीं हुआ ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजू को दस गोलियां लगीं, जिनमें से पांच गोलियां आठ से दस सेंटीमीटर व्यास में थीं— ऐसा लगता है कि ये गोलियां शरीर से सटाकर या बेहद करीब (पायंट ब्लैंक रेंज) से मारी गयी थीं। क्या राजू को उसी के किसी साथी ने पहले गोलियां मारीं और बाद में पुलिस की गोलियां भी उसके जिस्म में पहुंचा दी गयीं ?

मुठभेड़ के वक्त क्या हुआ ? : मुठभेड़ का कोई अधीकृत चश्मदीद गवाह नहीं है, सिवाय पुलिस के या मौके पर गिरफ्तार राजू के साथियों— घायल ओमप्रकाश और ब्रजमोहन के। इन दोनों से ही किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। लखनऊ पुलिस के सूत्रों के अनुसार घटनाक्रम कुछ इस प्रकार बनता है— एस०पी० सिटी लखनऊ को किसी से फोन पर सूचना मिली कि राजू भटनागर लाल रंग की फियेट कार में लखनऊ में देखा गया है। फिर उन्हें यह पता चला कि वह इलाहाबाद रवाना हो गया है। वह पुलिस के चुनिंदा अफसरों की टीम लेकर ९ जनवरी की रात को ही इलाहाबाद के लिए रवाना हो गये और मुखबिर से खबर पाकर राजू भटनागर को लाउदर रोड पर राजा बरांव की कोठी में स्थित मोटर गैरेज में घेर लिया। मुठभेड़ हुई और एस०पी० सिटी लखनऊ ने राजू भटनागर को मार गिराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मौके पर राजू भटनागर का गिरफ्तार घायल साथी ओमप्रकाश 'बबलू' पुलिस की गोली से घायल हुआ है, उसके गले, कमर और हाथ में गोलियां लगी हैं। लेकिन एक जानकार का कहना है कि ओमप्रकाश को लगी गोलियां यदि पुलिस के रिवाल्वरों से चली होतीं, तो उसका बचना नामुमकिन था।

इस प्रकार 'पुलिस मुठभेड़' की कहानी में दरारें-ही-दरारें दिखाई देने लगती हैं। मुठभेड़ के क्षणों में असल में क्या हुआ था— इस बारे में तरह-तरह की बातें शहर में होने लगीं। किसी का कहना था कि ओमप्रकाश ने गद्दारी की थी और इसका अहसास होने पर खुद राजू भटनागर ने ओमप्रकाश को गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। रोचक तथ्य यह है कि परंपरा के बावजूद पुलिस ने घायल ओमप्रकाश की तलाशी न लेकर, उसे सख्त पुलिस पहरे में मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचा दिया। ओमप्रकाश का इलाज कर रहे डाक्टर ने उसकी छह जीवित कारतूसों से लोडेड रिवाल्वर पुलिस को सौंपी थी। सवाल उठता है कि पुलिस ओमप्रकाश का संरक्षण मुखबिर की तरह क्यों कर रही है ? जबकि राजू गिरोह के प्रमुख सदस्य लक्ष्मीनारायण ओमप्रकाश उर्फ बबलू तथा शंकर दे की पैरवी कर रहे वकील एच०ए० अलवी इस बात से इनकार करते हैं कि बबलू 'ओमप्रकाश' राजू भटनागर से धोखेबाजी कर सकता है।

नया मोड़ : इस सारे काण्ड को लाल रंग की यूएचजी ७६७८ नवंबर की कांटेस्सा गाड़ी और भी रहस्यमयी बना रही है। माया की खोजबीन के अनुसार इस गाड़ी ने इस सारे काण्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह लखनऊ से इलाहाबाद आयी। घटनास्थल और कोतवाली पर भी देखी गयी, जहां दस जनवरी को पुलिस राजू-मुठभेड़ की जानकारी दे रही थी। (देखिए बाक्स) लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पुलिस कांटेस्सा गाड़ी के अस्तित्व से ही इनकार करती है, जबकि माया को अपने सूत्रों से पता चला है कि यह कांटेस्सा लखनऊ में राजू भटनागर के पास थी और इसी कार से वह लखनऊ से इलाहाबाद आया था। यह कार राजू को जिस राम प्रताप सिंह ने उपलब्ध करायी थी, वह भी अपराधी प्रकृति का आदमी बताया जाता है। यह भी पता चला है कि जिस होटल में लखनऊ से आयी

रहस्य कन्टेसा कार का

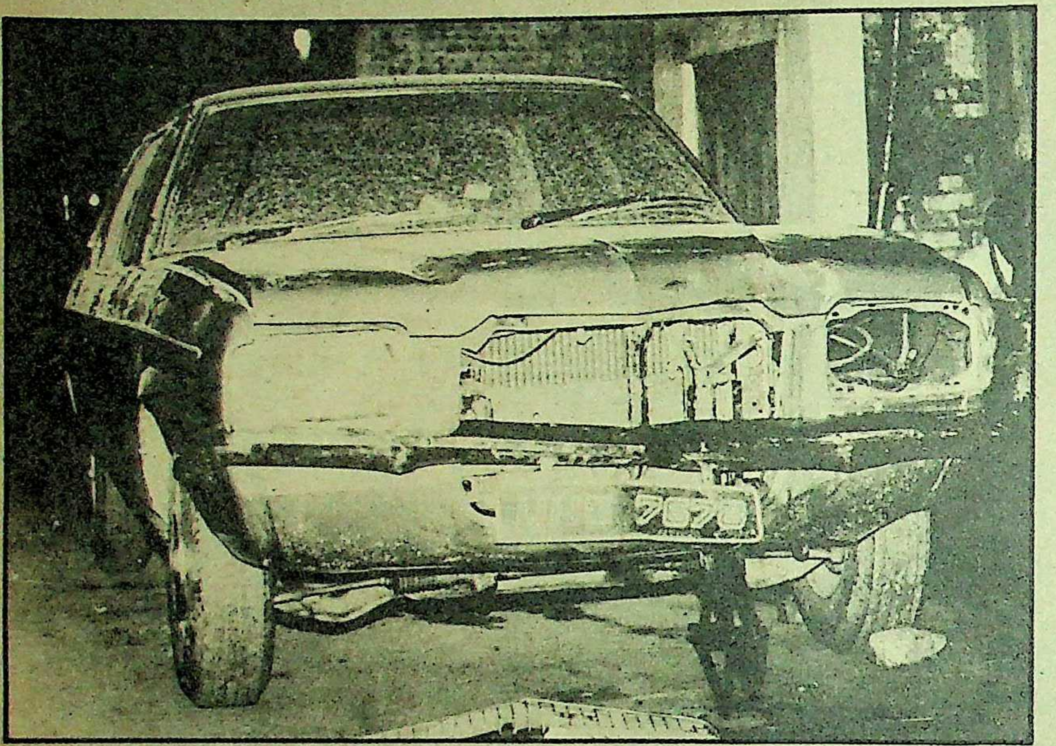

९ जनवरी की रात्रि लखनऊ पुलिस यू०एच०जी० ७६७८ नम्बर की जिस लाल फियेट कार में राजू भटनागर की तलाश कर रही थी, दरअसल, वह फियेट न होकर कन्टेसा थी। १० जनवरी को इलाहाबाद में राजू भटनागर के मुठभेड़ में मारे जाने की घटना के बाद जब लखनऊ के पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिंह इलाहाबाद कोतवाली में पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब भी वहां यही कार देखी गयी थी। उस समय इस कार में एक सिक्ख आया था और पुलिस अधीक्षक से बात कर कार सहित कहीं चला गया था।

आखिर ९ जनवरी की रात्रि लखनऊ में खोजी जा रही, यह कन्टेसा अगले दिन इलाहाबाद कैसे पहुच गयी। इस बारे में छानबीन करने पर 'माया' को कई चौंकानेवाले तथ्य प्राप्त हुए हैं।

१९८५ माडल की यह कार लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने खरीदी थी। उनके पास इसके पूर्व जो भी गाड़ियां थीं, उन सबका नम्बर ७६७८ ही था। प्रेस मालिक का कहना है कि इस नम्बर से उन्हें काफी लगाव था, क्योंकि यह उनके लिए 'लकी' नम्बर था। इसी कारण यह कार खरीदने के बाद उन्होंने विशेष आग्रह कर परिवहन विभाग से यू०एच०जी० ७६७८ नम्बर प्राप्त किया था। ढाई साल तक यह गाड़ी प्रेस मालिक के पास रही। इस अवधि में गाड़ी मात्र तीन हजार किलोमीटर ही चली थी।

इन्हीं प्रेस मालिक के एक मित्र बिक्रीकर अधिकारी थे जो अपना एक बड़ा प्लाट बेचना चाहते थे, इस प्लाट पर तमाम लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा था। कई लाख रुपए कीमतवाले इस प्लाट को प्रेस मालिक इस शर्त पर खरीदने को तैयार थे कि प्लाट बिलकुल खाली हालत में मिले। बिक्रीकर अधिकारी ने प्लाट पर नाजायज रूप से काबिज लोगों को बेदखल करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर रखा था। इसी बीच इस बिक्रीकर अधिकारी की भेंट महानगर निवासी राम प्रताप सिंह से हुई। राम प्रताप ने उनसे कहा, "अगर चार-पांच लाख खर्च करो, तो मैं प्लाट खाली करा सकता हूं।"

बिक्रीकर अधिकारी ने 'हां' कर दी। राम प्रताप सिंह, राजू भटनागर का साथी था। ओमप्रकाश उर्फ बबलू के साथ भी उसका उठना-बैठना था। महानगर में वहं सचिवालय कालोनी में रहता था। उसके पिता सचिवालय में सेक्सन आफिसर हैं।

राम प्रताप सिंह के विरुद्ध पुलिस में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन अपनी 'ऊंची पहुंच' के कारण वह पकड़ा नहीं जाता था। कई पुलिसकर्मियों से भी उसके संबंध थे।

राम प्रताप सिंह ने अपने 'प्रभाव' का इस्तेमाल कर प्लाट खाली करवा लिया। प्लाट खाली होते ही प्रेस मालिक ने उसे खरीद लिया। इसी के बाद २९ नवम्बर, १९८७ को उक्त प्रेस मालिक ने अपनी कन्टेसा कार बिक्रीकर अधिकारी को बेच दी। इस बारे में प्रेस मालिक का कहना था, "प्लाट के जो रुपए देने थे, उसी में ६० हजार रुपए 'एडजेस्ट' करने के लिए मैंने अपनी कार उन्हें दे दी थी।"

उधर प्लाट खाली कराने के 'मेहनताने' के साथ ही राम प्रताप सिंह ने बिक्रीकर अधिकारी से वह कन्टेसा 'उपहार' में ले ली। यह 'उपहार' उसे २५ दिसम्बर, १९८७ को मिला था। इस बारे में बिक्रीकर अधिकारी कहते हैं, "मैंने वह कार अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी। २४ दिसम्बर को राम प्रताप ने मुझसे कुछ दिनों के लिए कार मांगी, तो मैंने उसे दे दी। कार देते समय मैंने उससे लिखवा लिया था कि फिलहाल कार उसके 'पजेशन' में रहेगी।"

राम प्रताप ने २४ दिसम्बर को वह कार किसी खास उद्देश्य से मांगी थी। दरअसल, उस दिन ओम प्रकाश उर्फ बबलू को लखनऊ जेल से निकलना था। जेल से सुरक्षित निकलने के लिए एक कार की आवश्यकता थी, क्योंकि लखनऊ की पुलिस इस ताक में थी कि जैसे ही बबलू जेल से बाहर आये, उसे दबोच लिया जाये और उससे राजू भटनागर के ठोर-ठिकानों के बारे में पूछताछ की जाये। २४ दिसम्बर को पूरे दिन लखनऊ की पुलिस जेल के आसपास लगी रही। बबलू को इसकी भनक लग गयी थी। इसलिए वह जेल से निकला ही नहीं, लेकिन २५ दिसम्बर की भोर पांच बजे जेलकर्मियों को पटाकर बबलू बाहर आ गया। राम प्रताप, कन्टेसा लिये गेट पर ही खड़ा था। इसी कन्टेसा में बैठकर बबलू सुरक्षित निकल गया। दस बजे जब पुलिस जेल के गेट पर पहुंची, तो पता चला कि बबलू जेल से निकल चुका है।

उन दिनों राजू भटनागर लखनऊ के ही विकास नगर में फ्लैट नम्बर-२९३ में सुनीता के साथ आदित्य कुमार गुप्ता के फर्जी नाम से रह रहा था। उसने आस-पड़ोस के लोगों को अपने बारे में 'मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव' बता रखा था।

३१ दिसम्बर को इस कार का उपयोग राजू भटनागर ने किया था। उस शाम वह सुनीता के साथ इसी कार से लखनऊ के एक फाइव स्टार होटल में पहुंचा था और वहां आधी रात तक उसने 'न्यू ईयर ईव' मनायी थी। ४ जनवरी को सुनीता के साथ उसने अपनी शादी की दूसरी वर्ष गांठ भी बड़ी धूम-धाम से उसी होटल में मनायी थी। उस शाम भी वह इसी कार से होटल पहुंचा था।

९ जनवरी की शाम इसी कार में राजू को लखनऊ देखे जाने की खबर पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेश पाल सिंह को मिली थी।

उन्होंने तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिंह को उस कार की तलाश का आदेश दिया था, जिसके बाद वायरलेस पर इस कार का नम्बर देकर सभी थानों को सतर्क कर दिया गया था। फर्क केवल इतना था कि पुलिस को सूचना देनेवाले ने 'कन्टेसा' को 'फियेट' बता दिया था। सुरेश पाल सिंह को सूचना देनेवाले मुखबिर ने यह खबर थोड़ा विलम्ब से बतायी थी। इसी कारण तब तक वह कन्टेसा राजू को लेकर इलाहाबाद जा चुकी थी।

कन्टेसा से राजू को इलाहाबाद लेकर कौन गया, इस बारे में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। पुलिस के ही एक दरोगा का कहना है कि लखनऊ की एक कोतवाली के इंसपेक्टर ने राम प्रताप सिंह को अपना मुखबिर बना लिया था। राजू को इलाहाबाद पहुंचाने के बाद राम प्रताप ने वहीं से फोन कर इस इंसपेक्टर को राजू के ठिकाने की जानकारी दे दी थी।

लेकिन पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिंह कहते हैं, "मैं किसी राम प्रताप सिंह को नहीं जानता हूं। इलाहाबाद कोतवाली में भी न तो कोई कन्टेसा कार आयी थी और न ही मैंने उसमें सवार किसी सिक्ख से कोई बात की थी।"

१२ जनवरी की सुबह राम प्रताप ने उक्त बिक्रीकर अधिकारी के यहां जाकर सूचना दी, "आपकी कार लड़ गयी है। मैं उसे एक गैरेज में खड़ी कर आया हूं। आप उसे ले लें और ठीक करा लें।"

बिक्रीकर अधिकारी ने कहा, "मैंने वह कार तुम्हें दे दी है, अब वापस लेने का क्या सवाल।"

कोई एक घंटे बाद ही एक पुलिस इंसपेक्टर बिक्रीकर अधिकारी के घर पहुंचा और उनसे कहा, "आप राम प्रताप से अपनी गाड़ी ले लीजिए। ऐसे लोगों को गाड़ी देना ठीक नहीं रहता। 'क्रिमिनल' आदमी है, पता नहीं गाड़ी का क्या 'मिसयूज' (दुरुपयोग) कर ले।" इसी के बाद उक्त बिक्रीकर अधिकारी ने राम प्रताप द्वारा बताये गये गैराज से अपनी कार लाकर दूसरे गैराज में मरम्मत के लिए दे दी। उस समय कार के अन्दर सिगरेट के तमाम टुकड़े और 'पीटर स्काच' की दो खाली बोतलें पड़ी थीं।

बिक्रीकर अधिकारी पर जो इंसपेक्टर कार वापस लेने के लिए दबाव डालने गया था, वह इंसपेक्टर, लखनऊ से राजू भटनागर को मारने गयी पुलिस टीम में शामिल था। इस इंसपेक्टर का दावा है, "राजू को पहली गोली मैंने ही मारी थी।"

—संजीत सिंह, राजेन्द्र कुमार

सुनीता भटनागर

लक्ष्मीनारायण

पुलिस पार्टी ठहरी थी उसी होटल के कमरा नं० पांच में एक सरदार भी ठहरा था जो प्रातः ११ बजे से मुठभेड़ होने के काफी देर बाद तक मुठभेड़ स्थल का चक्कर लगाता नजर आया था। कोतवाली में भी वह उसी लाल कांटेस्सा कार से गया था, जहां कुछ लोगों ने उसे पुलिसवालों से बातचीत करते भी देखा था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एस०पी० सिटी लखनऊ एस०एन० सिंह इस घटनाचक्र में किसी सरदार के अस्तित्व से भी साफ इनकार कर गये। जानकार लोगों का कहना है कि यह सरदार लखनऊ के एक अन्य प्रभावशाली अपराधी गिरोह का आदमी है। राजू भटनागर गिरोह की वारदातों अकसर बुंदेलखण्ड, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ करती थीं, लेकिन इधर उसने कानपुर-लखनऊ क्षेत्र में भी वारदातें करनी शुरू कर दी थीं। वह अपराधी गिरोह नहीं चाहता था कि राजू गिरोह का प्रभाव इस इलाके में बढ़े। क्या इसी गिरोह ने पुलिस को सूत्र देकर राजू गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कराया और अंततः उसी ने राजू भटनागर की मौत का सारा सामान जुटा दिया? यह भी पता चला है कि इस गिरोह से वह पुलिस इंसपेक्टर भी परिचित है, जो मुठभेड़ में पुलिस पार्टी में मौजूद था और उसका दावा है कि राजू को पहली गोली उसी ने मारी थी। और १२ जनवरी को यही इंसपेक्टर कांटेस्सा के मालिक को मना करने गया था कि वह अपराधी किस्म के लोगों को अपनी गाड़ी न दिया करें।

राजू गिरोह: राजू भटनागर के पिता रामकृष्ण भटनागर राठ तहसील के बुधौलिया मुहल्ले में एक छोटा सा दवाखाना चलाते थे। उनके तीन पुत्रों और दो पुत्रियों में राजू उनका दूसरे नंबर का पुत्र था। उसके बडे भाई संतोष भटनागर उसे दतिया ले गये, ताकि पढ़ सके लेकिन वहां वह कुख्यात अपराधी सुरेश सोनी के संपर्क में आ गया और अपराध की दुनिया में यही सुरेश सोनी राजू का पहला गुरु बना। १९७३ में सुरेश सोनी ने कुलपहाड़ क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक बाबू राम पस्तौर की हत्या कर सनसनी फैला दी। वह पकड़ा गया था, लेकिन एक और कुख्यात अपराधी मनप्यारे के साथ १९७५ में जेल से भागकर उसने अपना गिरोह बना लिया। १९७६ में जब राजू भटनागर सुरेश सोनी के संपर्क में आया उस समय सुरेश के गिरोह में १८ सदस्य थे। २३ अगस्त, १९७६ को मनप्यारे मारा गया और २३ नवंबर, १९७७ को सुरेश सोनी दूसरी बार पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो आज तक जेल से निकल नहीं पाया। हमीरपुर जेल में जब उसे राजू भटनागर की मौत की खबर दी गयी, तो वह फूट-फूटकर रो पड़ा। उसका कहना था, "कुछ ही दिनों पूर्व राजू भटनागर मुझसे मिलने जेल आया था, तब मैंने उसे ये धंधे छोड़ने के लिए कहा, तो उसका जवाब था कि जेल की जिंदगी से मायूस होकर आप ऐसा कह रहे हैं।"

राजू-गिरोह जब सुरेश सोनी को जेल से रिहा कराने में असफल रहा, तो वह खुद इस गिरोह का सरदार बन गया और रईस घरानों व धनवान लोगों की उसने पकड़ शुरू कर दी। अपहरण करने का उसका एक खास लहजा था। जिसका अपहरण करना होता था, उससे वह पहले मधुर संबंध बनाता था और बाद में वह उसका अपहरण करके एक मोटी रकम उसके परिजनों से वसूल करता था। राजू के गिरोह में सभी युवक थे। इस गिरोह ने कानपुर से कृपा राम गुप्ता, मनोज कुमार अग्रवाल, लेडी डाक्टर मिनी जलोटा तथा ग्वालियर से मोहन और उसके भाई का अपहरण किया था। भूतपूर्व विशेष जज श्यामसुंदर पुरवार का अपहरण करके तो उसने तहलका ही मचा दिया था। १९८१ में गिरफ्तार होकर जब वह तिहाड़ जेल पहुंचा, तो वहां वह चार्ल्स शोभराज, राजेंद्र सेठिया जैसे शातिर अपराधियों के संपर्क में आया। दिसंबर, १९८५ में फर्जी जमानत पर तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद राजू ने फिर से अपना गिरोह संगठित किया। इसके गिरोह का कोई सदस्य ३२ साल की उम्र से अधिक नहीं था। इनमें सबसे ज्यादा लक्ष्मी नारायण (३२ वर्ष) था, जबकि राजू ३१ और सबसे कम उम्र का संतोष था। तिहाड़ से भागने के बाद राजू गिरोह अहपरण और बैंक लूटने की वारदातें करते हुए शहर-दर-शहर घूमता रहा। तिहाड़ जेल से मिलाई के दौरान एक कैदी की बहन सुनीता से राजू का संपर्क हुआ। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद राजू ने इसी सुनीता से शादी कर ली। १२ अगस्त, १९८६ को लखनऊ में राजू गिरोह ने दो पैट्रोल पंप लूटे और १९८७ में उसने सागर के धनाढ्यसेठ सुक्खी का अपहरण कर फिरौती में साढ़े पांच लाख वसूले थे। —राजू भटनागर एक काण्ड के बाद दूसरा काड करता जा रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। इधर पुलिस को यह भी सुराग मिला कि उसने कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद के उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारियों और नेताओं के आवासों और छात्रावासों को अपनी शरणस्थली बना लिया है।

अंत की शुरुआत: इस वर्ष ४ जनवरी को कानपुर में हुई बैंक डकैती से कानपुर पुलिस बौखला उठी थी। तभी उसे झांसी पुलिस से सूचना मिली कि चार्ल्स शोभराज के साथ जेल से फरार लक्ष्मीनारायण झांसी से दो व्यापारी पुत्रों का अपहरण कर लखनऊ पहुंच रहा है। सुराग लगाते-लगाते कानपुर पुलिस लखनऊ जा पहुंची और उसने लक्ष्मीनारायण को बंदी बनाकर व्यापारी पुत्रों को मुक्ति दिलाई। पुलिस ने अपने ढंग से पूछताछ की, लेकिन लक्ष्मीनारायण ने राजू भटनागर के बारे में कुछ भी बताकर नहीं दिया। बहरहाल, लखनऊ पुलिस इस बात से अपमानित महसूस कर रही थी

राजू भटनागर के संरक्षणदाता

‘मनोहर कहानियां’ से १९८१ में हुए एक लंबे साक्षात्कार में राजू भटनागर ने कहा था, “एक बात मैं बताना चाहता हूं। बड़े-बड़े राजनेता मेरे मित्र और शुभचिंतक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधायक एवं सांसद कक्षों में मैं रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, जिनमें मंत्री भी हैं और ये यह जानते भी हैं कि मैं क्या कर रहा हूं।” उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकार्ड के अनुसार राज्य के पांच सांसदों, डेढ़ दर्जन विधायकों और करीब तीस से अधिक राजनेताओं का राजू भटनागर और उसके साथियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण प्राप्त था।

१० जून, १९८१ को जब राजू भटनागर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उसने पूछताछ के दौरान यह बात स्वीकार की थी कि झांसी परिक्षेत्र के डी०आई०जी० ओंकार शर्मा के यहां वह अकसर ठहरता था। उसने ओंकार शर्मा के पुत्र से अपनी मित्रता की बात भी पुलिस को बतायी। तब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक नरेश कुमार को राजू भटनागर द्वारा दिये गये बयान की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी।

नरेश कुमार ने राजू के इस बयान को काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने राज्य के गृहमंत्रालय को इस स्थिति से अवगत कराते हुए एक पत्र भी लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि यह बड़े शर्म की बात है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की राजू भटनागर जैसे शातिर अपराधी से साठगांठ है। उन्होंने संस्तुति की थी कि इस पुलिस अधिकारी की पदावनति कर दी जाये।

नरेश कुमार की इस संस्तुति तथा एक डी०आई०जी० से राजू के सम्पर्क ने पुलिस विभाग में सनसनी फैला दी थी। लेकिन जैसे ही नरेश कुमार पुलिस महानिदेशक के पद से हटे, ओंकार शर्मा की पदोन्नति कर उन्हें महानिदेशक बना दिया गया।

दर्जनों प्रभावशाली और सत्ताधारी लोगों के राजू से घनिष्ठ संबंध थे। झांसी के ही एक भूतपूर्व गृहराज्यमंत्री और बुन्देलखंड के एक सांसद के यहां राजू और उसके गिरोह का बेहिचक आना-जाना था। लखनऊ के एक माफिया सरगना रामगोपाल मिश्र गिरोह के तीन सदस्य शंकर डे, बबलू और शेरिफ तो राजू के साथ मिलकर अपराध करते थे। रामगोपाल मिश्र को वीर बहादुर मंत्रिमंडल के एक सदस्य का खुला संरक्षण प्राप्त है। पिछले दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में रामगोपाल ने जमकर इन मंत्री का चुनाव प्रचार किया था।

राजू भटनागर के लिए भोपाल एक निरापद अभयारण्य था। १९८२ में उसने यहां भारी किराये पर दस से अधिक मकान ईदगाह हिल्स, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, विद्यासागर, पुल बोगदा, पंजाबी वार्ड, कोटरा सुलतानाबाद आदि में लिए थे, जिनमें ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद रहते थे।

राजू के संरक्षणदाताओं में दतिया (म०प्र०) नगरपालिका के सदस्य वीरेंद्र कुमार उर्फ लिल्ली तथा भूतपूर्व इंका विधायक सेठ गुलाबचंद्र भी थे। इन्हें १९८१ में राजू की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

गत वर्ष भी सागर से सुक्खी सेठ की पकड़ के बाद राजू पन्ना से सात कि०मी० दूर जंगल में बने जिस झलाई कोठी में गया था, वह पन्ना के नन्हें राजा की पुरानी शिकार गाह है, जिसके मौजूदा मालिक कुंवर भूपेंद्र सिंह बताये जाते हैं। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के गृहराज्य मंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह के रिश्तेदार और पन्ना जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कैप्टेन जयपाल सिंह, पन्ना के निवासी हैं और यहां के पवई क्षेत्र से विधायक हैं। सुक्खी अपहरण कांड के एक पात्र बिहारी चतुर्वेदी का पहाड़ गांव छतरपुर के राजेंद्र सिंह से संपर्क रहा है। राजेंद्र सिंह झलाई कोठी वाले भूपेंद्र सिंह के सगे बहनोई हैं। बताया जाता है कि सुक्खी सेठ के अपहरण के सिलसिले में पकड़े गये उमाशंकर की, झांसी क्षेत्र के इंका सांसद सुजान सिंह बुंदेला से जान-पहचान रही है। भूपेंद्र सिंह के बड़े भाई महेंद्र सिंह सुजान सिंह बुंदेला के बहनोई हैं।

वर्ष १९८६ में राजू भटनागर और उसके साथियों ने लखनऊ में दो पेट्रोल पम्प लूटे थे। लूट की इस वारदात में शामिल एक अपराधी प्रभात दीक्षित को लखनऊ पुलिस ने २३ अक्टूबर, १९८६ को एक इंका विधायक (विधानपरिषद सदस्य) डी०एच० अंसारी के दारूलसफा स्थित कमरे से गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज के साथ फरार हुए राजू भटनागर के साथी बृजमोहन को जब अक्टूबर, १९८६ में कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उसके पास से प्रदेश इंका के एक महामंत्री दल सिंगार यादव द्वारा लिखे तीन पत्र बरामद हुए थे। बाद में श्री यादव ने कहा था कि जिस पैड पर यह पत्र लिखें हैं, यह तो उनके हैं लेकिन पत्र फर्जी हैं।

इसी प्रकार वर्ष, १९८४ में जब राजू गिरोह के एक सक्रिय सदस्य ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू (जो इलाहाबाद में राजू से हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है) को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध रासुका की कार्यवाही शुरू की थी, तो इंका विधायक दीनानाथ पांडेय ने २४ जनवरी १९८४ को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था, “श्री श्रीवास्तव, एक अच्छे घर का सीधा-सादा लड़का है, विधि स्नातक भी है। इसलिए उसके ऊपर से मीसा उठा लेने के आदेश देने की कृपा करें।”

बाद में उच्चराजनीतिक संरक्षण के कारण ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू को लखनऊ के अपर जिला मजिस्ट्रेट ने १६ अप्रैल, १९८७ को जेल में उच्चश्रेणी प्रदान की। इस सिलसिले में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने १८ अप्रैल, १९८७ को जिला कारागार अधीक्षक को एक पत्र लिखा। पत्र की संख्या है—मे पो/उ०प्र०—जे०ए०—३।

इलाहाबाद में पकड़े गये राजू के साथी बृजमोहन सिंह के बारे में भी काफी चौंकानेवाले तथ्य प्रकाश में आये हैं। बृजमोहन मूल रूप से फैजाबाद का रहनेवाला है। उसके बड़े भाई जगमोहन सिंह, राज्य के भूतपूर्व मंत्री संजयसिह के काफी नजदीक हैं। संजय सिह जब परिवहन मंत्री थे, तब उन्होंने जगमोहन सिंह को राज्य परिवहन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया था। जब संजय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो जगमोहन भी प्राधिकरणं की सदस्यता से त्यागपत्र देकर जनमोर्चा में शामिल हो गये। पुलिस अब इस बात की सरगर्मी से छानबीन कर रही है कि क्या जगमोहन के राजू भटनागर से कोई संबंध थे। नवाबगंज (गोंडा) के एक प्रमुख इंकाई तथा कथित माफिया सरगना बृजमोहन सिंह से राजू के संबंधों का भी पुलिस को पता चला है।

राजू की निगाह में संरक्षण पाने के सबसे सुरक्षित स्थान विश्वविद्यालय के छात्रावास तथा नवनिर्मित कालोनियों के फ्लैट्स थे। उसकी मान्यता थी कि छात्रावासों में कुछ छात्रों को अच्छी दावतें देकर आसानी से उनके साथ ठहरा जा सकता है। इसी तरह नयी बनी कालोनियों में ऊंचे किराये का फ्लैट लेकर रहने में भी असुरक्षा का भय नहीं रहता। नयी कालोनियों में आस-पड़ोस के लोग एक-दूसरे के बारे में जानने की चिन्ता ही नहीं करते हैं। इसी प्रकार छात्रावास में भी पुलिस आसानी से प्रवेश नहीं करती है।

—अजय कुमार

कि लक्ष्मीनारायण और राजू भटनागर उनकी ही नाक के नीचे लखनऊ में शरण पाते हैं। पुलिस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार लखनऊ पुलिस को राजू भटनागर के एक सहयोगी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू के बारे में जानकारी मिली, लेकिन खोजबीन के बाद उसका कहीं पता न चला। इसी बीच पुलिस को १५ वर्षीय किशोर यासीन हाथ लग गया। यासीन के जरिये बबलू को पकड़ लिया गया। थोड़ा ना-नुकुर के बाद बबलू राजू भटनागर का पता लगाने पर राजी हो गया। उसने यासीन को 'जलील' के कोडनाम से मध्यस्थ बनाया, जिससे उस पर किसी को शक न हो। ९ जनवरी की शाम पुलिस को जलील से सूचना मिली कि राजू भटनागर लाल रंग की फियेट कार में, जिसका नंबर यूएचजी ७६७८ है, देखा गया है और इसी सूत्र ने लखनऊ पुलिस को इलाहाबाद पहुंचा दिया। इस समय राजू के साथ हुई कथित मुठभेड़ के वक्त गिरफ्तार उसके साथी ओमप्रकाश उर्फ बबलू का अस्पताल में उपचार हो रहा है और ब्रजमोहन जेल में है। पुलिस ने गैराज के मालिक मकसूद और एक पेंटर को भी हिरासत में ले लिया है। मुठभेड़ की असलियत पर अभी तक भी कोहरा छाया हुआ है। झांसी पुलिस लक्ष्मीनारायण का सुराग देने, कानपुर पुलिस लखनऊ से लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार करने, लखनऊ पुलिस इलाहाबाद तक पहुंचकर राजू को मार गिराने और इलाहाबाद पुलिस इस मुठभेड़ में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए राजू के सिर पर घोषित इनाम में अपनी हकदारी साबित करने में जुटी है। राजू की पत्नी सुनीता दिल्ली पुलिस की शरण में चली गयी है। बहरहाल, राजू की इलाहाबाद में दिन-दहाड़े हुई हत्या अपने पीछे कई और ऐसे सवाल छोड़ गयी है, जिनके उत्तर नहीं मिलते। सबसें बड़ा सवाल यही है कि क्या लखनऊ पुलिस राजू भटनागर के बारे में पहले से जानती थी और उसपर उसने तभी हाथ डाला, जब कानपुर पुलिस ने लखनऊ चुपचाप आकर लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार कर उसे लज्जित किया। अथवा कुछ बड़े लोगों ने अपने काले चेहरों के उजागर होने के भय से राजू भटनागर की मौत की हरी झंडी पुलिस को दे दी अथवा दूसरे अपराधी गिरोह ने खुद राजू भटनागर को मुर्दा हालत में पुलिस को पेश कर दिया, जिससे वह मुठभेड़ का यश प्राप्त कर सके।

बताया जाता है कि राजू ने एक बीड़ी व्यापारी के किसी सदस्य का अपहरण करने के उद्देश्य से इलाहाबाद में डेरा डाला था और दस जनवरी को वह ऐसी ही वारदात करने के लिए फैजाबाद रवाना होनेवाला था। वैसे तो वह कई फर्जी नामों से रहता था, लेकिन इलाहाबाद में जब वह मारा गया, तो उसने ठेकेदार सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अपना परिचय दिया था और इलाहाबाद के एक छात्रावास में एल०एल०एम० के छात्र ब्रजमोहन के साथ ठहरता था। ब्रजमोहन 'मुठभेड़ स्थल' से ही गिरफ्तार हुआ था।

—अजय कुमार

यदि आई०जी० स्तर पर 'मुठभेड़ की असलियत' की निष्पक्ष जांच हुई, तो बहुत संभव है, कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आयें। राजू भटनागर नहीं रहा—वह अपने साथ ऐसे रहस्य भी ले गया जो ऊंचे पदों पर बैठे अनेक लोगों के बदनुमा चेहरों को बेनकाब कर सकते थे।

कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब
चुटकी पान मसाला खाईए जनाब
सौंफ इलायची छुआरे वाला
चुटकी
पान मसाला
Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"
Chutki
CHUTKI
चुटकी
के॰के॰ कार्यालय का उत्कृष्ट उत्पादन

सीमांत गांधी

एक युग पुरुष का अंत

आजादी की लड़ाई के अन्यतम सिपाही बादशाह अब्दुल गफ्फार खां का ९८ साल की उम्र में २० जनवरी को पेशावर में इंतकाल हो गया। सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, खुदाई खिदमतगार, फ्रंटियर गांधी, बाचा खां आदि कई नामों से मशहूर बादशाह खां अपनी तमाम जिंदगी कौम की खिदमत करते रहे। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक २२ जनवरी को उनके शव को जलालाबाद (अफगानिस्तान) में दफना दिया गया।

अजीम शख्सीयत के मालिक अब्दुल गफ्फार खान का जन्म अविभाजित भारत के पेशावर जिले के उतमानजई गांव में हुआ था। ब्रिटिश अफसरों के व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ी और कौम में इल्म की रोशनी जगाने में जुट गये। १९१९ में रोलेट ऐक्ट की खिलाफत करते हुए उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। बाद में वह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नजदीक आये। १९३० में उन्होंने 'खुदाई खिदमतगार' संगठन बनाया और उसके सदस्य 'लाल कुर्ती धारी' कहलाये। सरहद पर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें 'सरहदी गांधी' का खिताब हासिल हुआ। अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा उन्होंने जेल में ही बिताया।

आजादी के बाद मुल्क के बंटवारे को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया और हमेशा इसे एक 'दुर्घटना' करार दिया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ज्यादातर फौजी तानाशाही रही और उन्होंने उसकी खिलाफत करते हुए 'पख्तूनिस्तान' की मांग बुलंद की जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को हमेशा नागवार गुजरी। पाकिस्तानी हुकूमत में आजादी के बाद भी 'खान' ज्यादातर जेलों में कैद रहे। १९६४ से १९७२ के बीच उन्होंने पाकिस्तान से निर्वासित जीवन बिताया।

१९६९ में उन्हें अंतरराष्ट्रीय सद्‌भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले साल १५ मई को इलाज के लिए उन्हें हिंदुस्तान लाया गया था तथा इलाज के बाद २६ जून को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी। इसी बीच उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया। १६ अगस्त को उन्हें एक खास विमान से पेशावर ले जाया गया। लेकिन शायद उन्हें पाकिस्तानी हवा रास नहीं आयी और वह फिर बीमार हो गये। काफी अरसे तक 'कोमा' में रहने के बाद ९ जनवरी को उनकी हालत और बिगड़ गयी और फिर आखिर तक नहीं संभल सकी।

बादशाह खां की ख्वाहिश थी कि वह एक फौजी की जिंदगी जियें और मरें भी तो एक फौजी की मौत और निश्चित रूप से उन्हें किसी फौजी से कमतर मौत नसीब नहीं हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपने विदेश दौरे को रोक कर बादशाह को श्रद्धांजलि देने पेशावर गये।

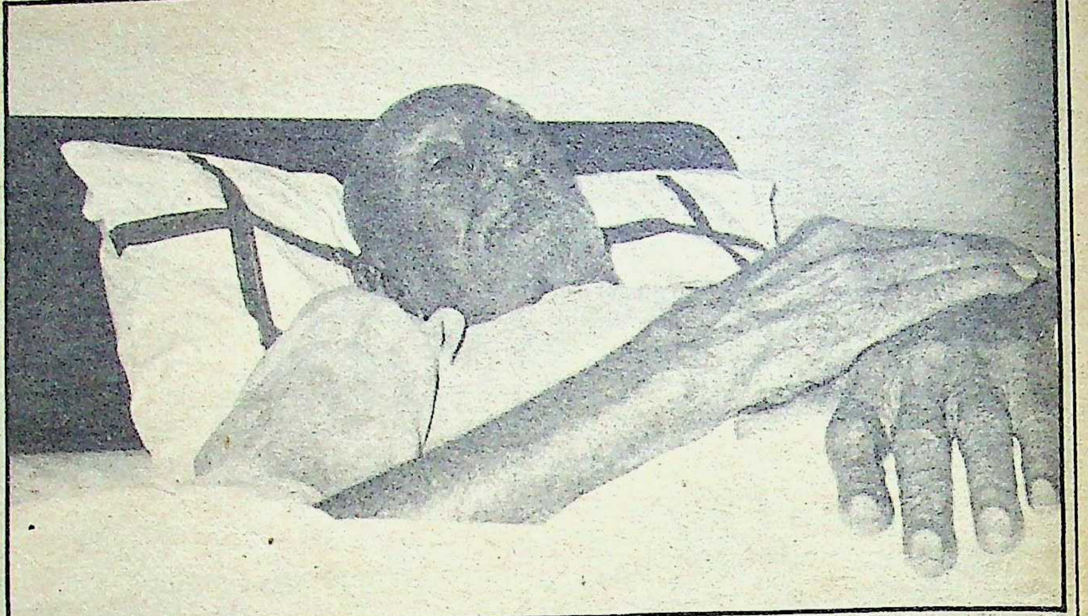

अखड भारत का सपना अधूरा रह गया : गफ्फार खां जब इलाज के लिए भारत आये थे

खुदाई खिदमतगार : पं० नेहरू के साथ गफ्फार खां

नेहरू, इंदिरा और शेख अब्दुल्ला के साथ गफ्फार खां

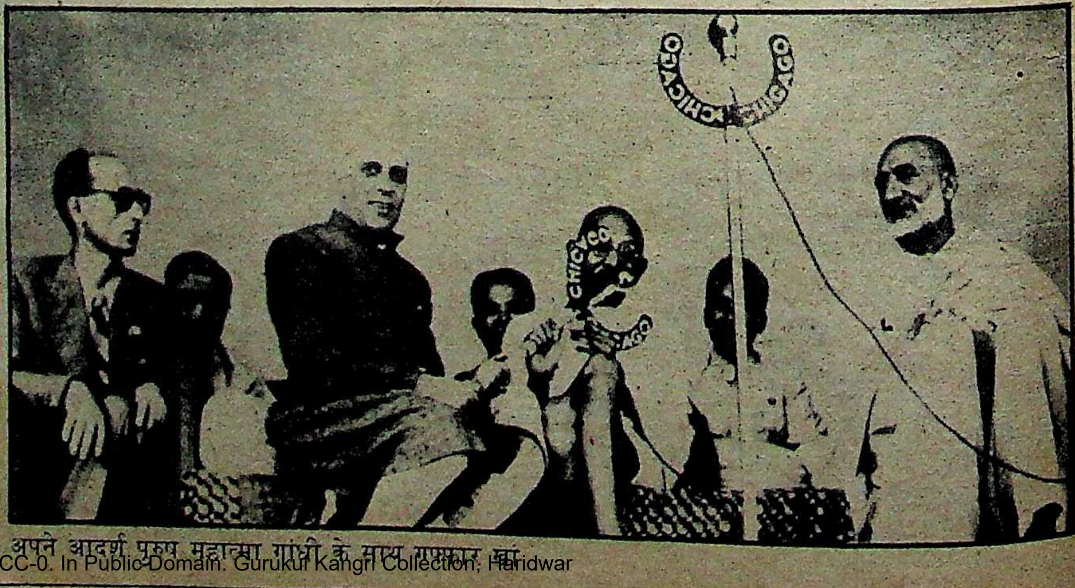

अपने आदर्श पुरुष महात्मा गांधी के साथ गफ्फार खां

Rajnigandha
ताज़गी के पल...
...एक पल में ताज़गी
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
रजनीगन्धा
पान मसाला

शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम छाया: डी०आर० यादव

शत्रु उवाच !

अपनी ही हाजिरजवाबी के कायल शत्रुघ्न सिन्हा समूची फिल्म इंडस्ट्री में घबड़ाते हैं, तो सिर्फ जाट-हीरो धर्मेंद्र से, कतराते हैं, तो सिर्फ खान-बंधुओं-संजय खान व फीरोज खान से तथा बर्राते हैं, तो गंजे राजकुमार से। वरना वह दिल्ली दरबार से लेकर शहंशाह (अमिताभ बच्चन) तक को कुछ नहीं समझते।

इधर तीन-तीन फिल्मों की व्यावसायिक सफलता के बाद उनके रामायण-दरबार और स्टूडियो-दरबार में हाजिर होने वाले दरबारियों की भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। वह बड़े मुक्त कंठ से प्रवचन देते हैं, "ऊ एक ठौ ठहरा बीमार (अमिताभ बच्चन), दूसर ठहरा पियक्कड़ (विनोद खन्ना) और हम ठहरे लेटलतीफ! सो डिरेक्टर लोग भाग कर अब हमरे-पास आवत हैं कि सतरू भैया लेट सही, लेकिन आंवत तो हैन।" अब पता नहीं शत्रु के इस उवाच को अमिताभ व विनोद ने सुना या नहीं !

रेखा आंटी की भतीजे पांडे से दोस्ती

जब से राज बब्बर, शत्रु, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने तीसरे नंबर के नायकोंवाली भूमिकाएं निभानी तथा अपनी कीमत में कमी कर दी हैं, गोविंदा ने निर्माताओं से अपने रिश्ते सुधार लिये हैं, डांसिंग स्टार चंकी पांडे की मुसीबत हो गयी है। शत्रु और राजकुमार की लीक पर बड़बोले बन जानेवाले चंकी की यह आदत भी निर्माताओं-निर्देशकों को कुछ इस कदर नागवार गुजरी कि कमबोले सुमीत सहगल की ओर रुख करने लगे और बड़बोली मामा (मां) डा० स्नेहलता पांडे का सारा पब्लिसिटी 'चक्कर' नाकाम हो गया। मामा-पांडे की असफलता ने बेटे-पांडे को ही कुछ नये नुस्खे आजमाने के लिए प्रेरित किया, तो वह सीधे आंटी रेखा के पास पहुंचे। वहां आयकरवालों के छापे से रेखा दुखी थीं। मौका देखकर-चंकी पांडे ने रेखा के दुखी दिल को सहलाने और मरहम लगाने का काम शुरू कर दिया जिससे रेखा को मानसिक सकून मिला। अपने से १० वर्ष छोटे संजू के अफेयर में वर्षों पहले दिल जला बैठी रेखा की अपने से १३ वर्ष छोटे चंकी के साथ बढ़ रही दोस्ती पापा-पांडे को कतई पंसद नहीं, लेकिन मामा-पांडे इसे चाची-भतीजे की दोस्ती का नाम देकर खुद को और घरवालों को संतोष दिला ले लेती हैं और बेचारा बेटा हर सुबह मरहम पट्टी लगाने रेखा के बांद्रा स्थित 'सी-बर्ड' बंगले पर पहुंच जाया करता है।

गोविंदा और सुमीत सहगल की मांओं को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए !

चंकी पांडे और रेखा छाया: एन० प्रसाद

सुधा चंद्रन का खौफ

आपको पता है डिंपल कपाड़िया किससे खौफ खाती हैं? कार-दुर्घटना में एक पैर खो बैठी 'मयूरी' सुधाचंद्रन से।

सेंसर की दोमुंही नीति की शिकार तथा उसके पंजे में फंसी अभिनेत्री साधना के पति आर०के० नैयर की फिल्म, 'पति-परमेश्वर' में डिंपल और सुधा ने साथ-साथ भूमिकाएं निभायीं। जब फिल्म बन रही थी, तो डिंपल की फिल्म बाक्स आफिस पर पिट रही थीं और दिनोदिन मिल रही लोकप्रियता तथा असफलता के कारण सुधा चंद्रन 'नाचे मयूरी' हो रही थीं। कुंठित डिंपल के 'कमेंट्स' को सुधा तो चुपचाप सह लेती, लेकिन माधवी को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक फिल्म में माधवी के साथ डिंपल का कीचड़ युद्ध दृश्य फिल्माया जाना था, इत्तिफाक से शूटिंग के दिन उसी स्टूडियो के दूसरे सेट पर डिंपल को 'दो बेटियों की बूढ़ी मां' जैसा राग अलापनेवाले राजेश खन्ना को कार से उतरते देख कर डिंपल बौखला गयी। फलतः पहले से भरी हुई दोनों अभिनेत्रियों ने कीचड़ युद्ध को कुछ इतना

सुधा चंद्रन छाया: रथिजीत घटक

रियलिस्टिक बना दिया कि सेट पर उपस्थित लोगों ने वाह-वाह कर दी, लेकिन 'टेक' हो जाने के बाद भी जब वे एक-दूसरे से भिड़ी रहीं, तो निर्देशक को शंका हुई। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग-अलग किया जा सका।

'पति परमेश्वर' की शूटिंग जब निकटता के करीब आयी तब तक 'इंसाफ' की सफलता के बाद डिंपल स्टार बन चुकी थी और बड़प्पन के बोझ तले दबी डिंपल सुधा पर कमेंट्स से बाज नहीं आयी। लेकिन एक दिन अचानक उसका रवैया बदला-बदला नजर आने लगा। उसके सारे कमेंट्स सुधा की तारीफों में बदल गये। कारण? एक दिन डिंपल को उसकी एक खास चमची ने बतलाया, "सुधा कह रही थी कि माधवी ने तो उसे कीचड़ में झिझोड़ा था, मुझसे टकरायेगी, तो मैं अपनी नकली टांग से उसका चेहरा ऐसा बदल दूंगी कि वह दो बेटियों की मां नहीं दादी लगने लगेगी।" बस डिंपल डर गयी और उसका रवैया बदल गया, यों सुधा का कहना है कि उसने ऐसी बात कही ही नहीं थी।

मीनाक्षी का 'न्यू इयर रिजोल्यूशन !'

वृश्चिक राशिवाले बड़े संवेदनशील एवं रोमांटिक होते हैं, लेकिन 'कोल्ड स्टोरेज' के नाम से अभिनेताओं में बदनाम मीनाक्षी शेषाद्रि के वृश्चिक राशि का होने पर जब लोगों ने संदेह करना शुरू कर दिया, तो उसने भी अपने को वृश्चिक राशि का प्रमाणित करने के लिए कमर कस ली। जिस चंकी पांडे और चिपू कपूर को वह पहले लिफ्ट नहीं दिया करती थी, उन्हें ही एक फिल्म मुहूर्त में सामने खड़ा देखकर उनके साथ कुछ ऐसा 'गर्म रोमांटिक' व्यवहार किया कि लोग सकते में आ गये। हमेशा कतरानेवाले सन्नी देवल तथा 'पेंटर बाबू' में उसका भरपूर एक्सप्लायटेशन करनेवाले भारत अंकल उर्फ मनोज कुमार को भी उसने नहीं बख्शा।

लेकिन बुरा हो मीनाक्षी का बुरा चाहनेवाले गपोड़ियों का कि उन्हें यहां भी गाशिप और स्कूप ही नजर आया। उन्होंने मान लिया कि मीनाक्षी ने यह सारा नाटक अपने भूतपूर्व ब्वाय फ्रेंड जैकी और उसकी नयी-नवेली दुल्हन आयशा को जलाने के लिए किया है, वरना वह तो इतनी 'कोल्ड' है कि जब सनी उस पर 'टांट' मारता था, तो वह शर्म से दुहरी हो जाया करती थी।

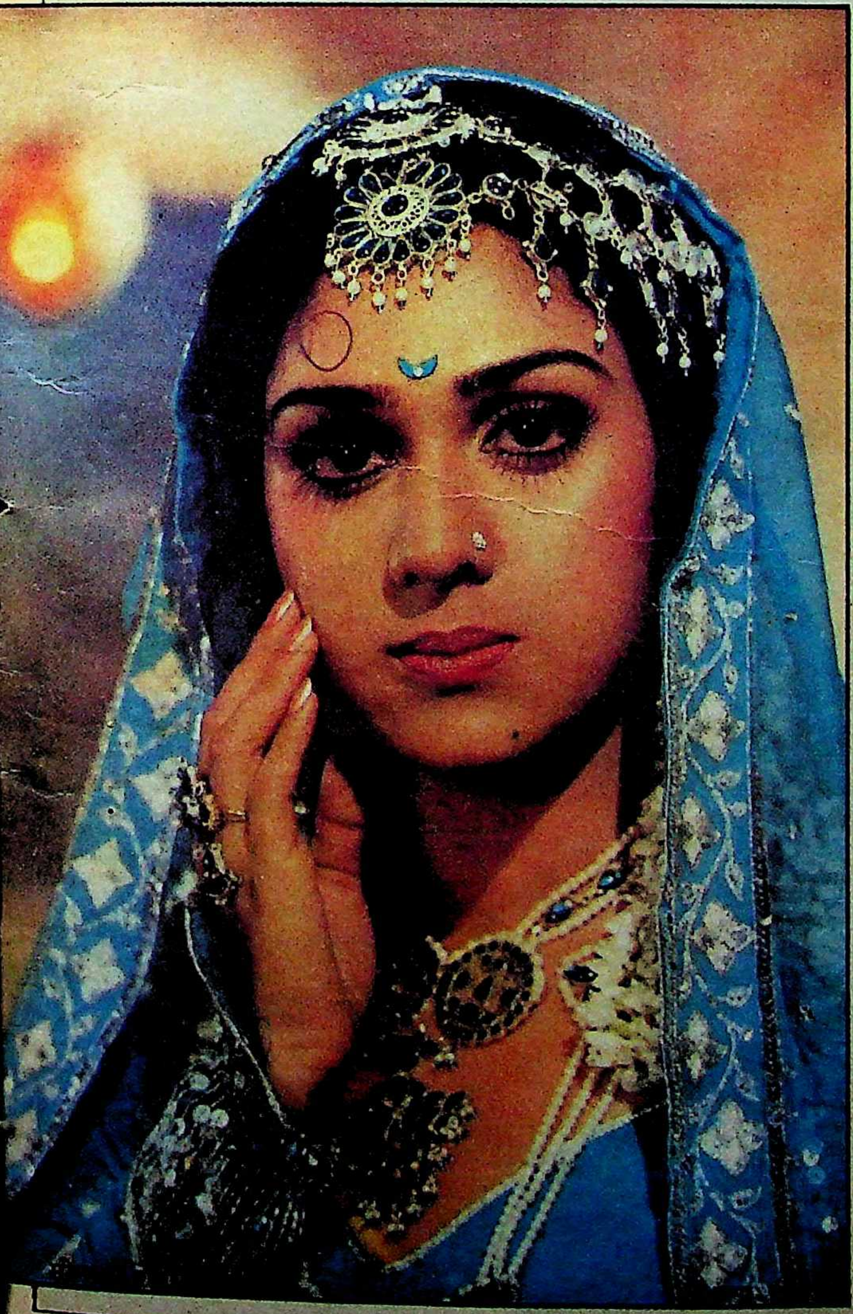

नीलम-फरहा : कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती।

हांगकांग की नीलम और हैदराबाद की फरहा ने 'लव ८६' में ऐसी गाढ़ी दोस्ती पाली कि पूरे सन् १९८६ भर उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती रहीं, फिर उनकी दोस्ती १९८७ में कुछ ऐसी दुश्मनी में बदली कि उनकी दुश्मनी के चर्चे मिसाल बनने लगे। सन् १९८७ के समापन के साथ-साथ दोस्ती की नींव पर बनी दुश्मनी की कब्र अचानक ढह गयी और फिर वे दोस्त बन गयीं। ३१ दिसंबर '८७ की रात दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी। वे अपने ब्वाय फ्रेंडों को बिसराकर, तब तक एक-दूसरे के हाथ-में-हाथ डाले नाचती रहीं जब तक कि थक कर बैठ नहीं गयीं।

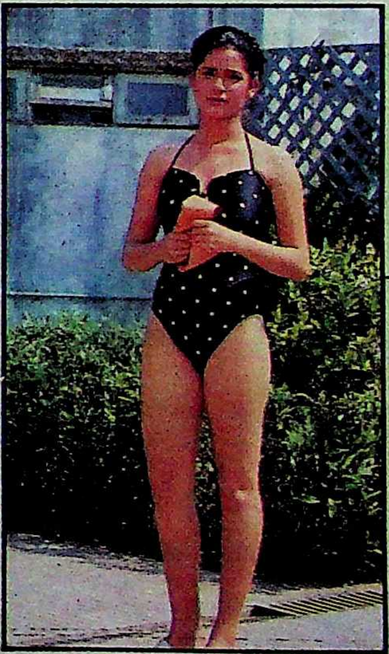

नीलम छाया : टी०एन०ए० प्रसाद

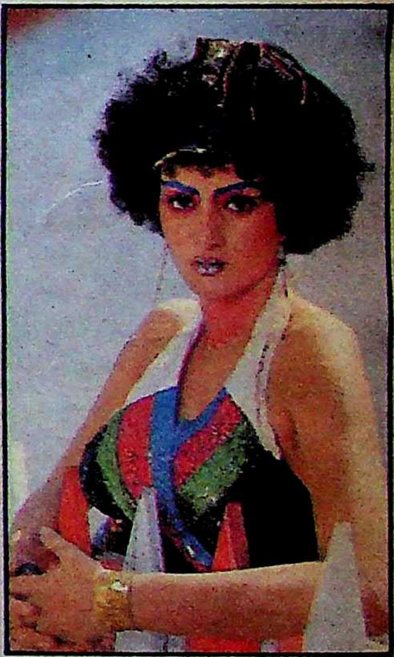

फरहा छाया : डी०आर० यादव

नीलम-फरहा की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का श्रेय सोनम को जाता है, जबकि सन् १९८६ की उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का श्रेय मंदाकिनी को गया था। सोनम ने उनके बीच की खाई को ही नहीं पाटा है, बल्कि सन् १९८७ में ली गयी उनकी कसमों को तुड़वा भी दिया है।

सन् '८७ के न्यू ईयर रिजोल्यूशन में नीलम और फरहा ने कसम खायी था कि वे न तो फिल्मों में चुंबन देंगी (गोविंदा के कहने पर भी!) न स्विमिंग कास्ट्यूम या बिकनी पहनेंगी और न ही ग्लैमरस रोल करेंगी। वे फ़िल्म निर्माताओं को बैरंग लौटा रही थीं कि नयी-नयी आयी सोनम ने ७५ प्रतिशत की 'छूट' दे कर नीलम-फ़रहा द्वारा लौटाये जा रहे फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को हथिया लिया।

भला हो सोनम का कि उसके बढ़ते स्टारडम से घबड़ाकर दोनों की कुट्टी और कसम की छुट्टी हो गयी। यह बात दीगर है कि अब वे दोनों सोनम को 'दुश्मन न० १' मानने लगी हैं।

फरवरी प्रथम पक्ष १९८८

मनोरमा

कढ़ाई विशेषांक

एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइनें

विशेष रचनाए

- ० पॉपी के फूलों का गुलदस्ता
- ० एक नमूना किशोरों के लिए
- ० बाग की सुंदरता निहारती नारी
- ० एक लैण्डस्केप
- ० आंचल
- ० टी०वी० कवर
- ० तीस नमूने कढ़ाई के
- ० नया नमूना : हर्बल टावर
- ० पक्षीवाला वॉल पैनल
- ० प्रेम का उपहार : चीटू-नीटू
- ० मां मरियम की गोद में यीशू
- ० कढ़ा हुआ पैचवाला पीला कुर्ता
- ० सिद्धि विनायक गणेश
- ० राजस्थानी दम्पती
- ० कढ़ी बेल का निखार

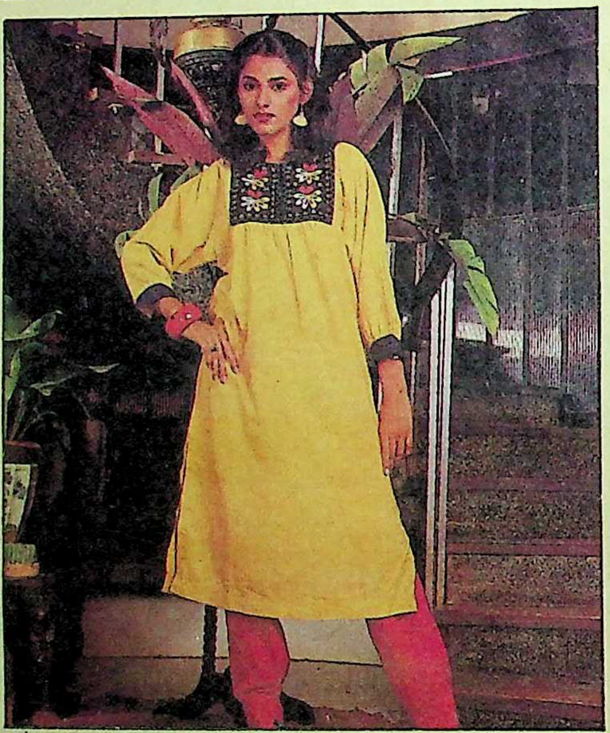

आवरण कथा :

क्या आप बच्चों को सही तरीके से पढ़ा रही हैं ?

बढ़ते हुए लंबे-चौड़े पाठ्यक्रम की वजह से आज बच्चों की पढ़ाई, बच्चों पर और उनके मां-बाप पर भी एक ऐसा बोझ है, जिसे कम करने की जिम्मेदारी अभिभावक के ही हिस्से में आती है। पर यह जिम्मेदारी प्रायः उनके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि वे कोई प्रशिक्षित अध्यापक तो होते नहीं। यदि आप भी इस समस्या की गिरफ्त में हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।

अन्य आकर्षण

सौन्दर्य : अगर बाल जी का जंजाल हो

सुहागरात : सोचा था कुछ और हुआ कुछ और

फैशन : पारम्परिक डिजाइनें : आधुनिक रंग

चक्रव्यूह : कहानी एक नवयुवती की नीलामी की

फिल्म : एक हरफनमौला कलाकार : नसीरूद्दीन शाह

कहानी— रूपवती

ज्ञानेन्द्रनाथ श्रीवास्तव का हास्य व्यंग्य— विज्ञापन माहात्म्य

मूल्य ६.००

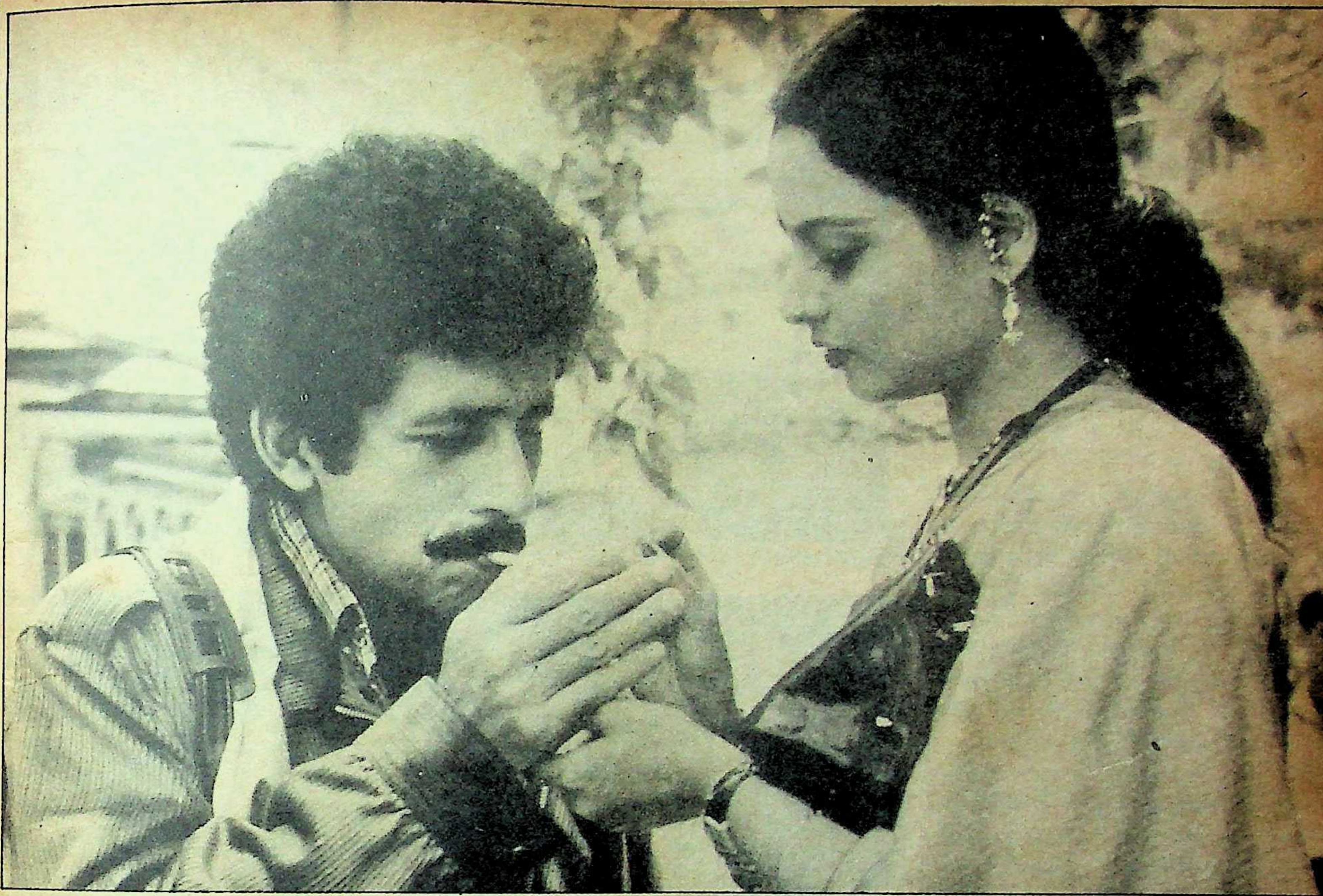

गुलजार निर्देशित फिल्म 'इजाजत' में नसीरुद्दीन शाह और रेखा

आठवां फिल्मोत्सव

विवादों के बीच एक तमाशा

हर साल फिल्मोत्सव की शुरुआत किसी-न-किसी विवाद के साथ होना मानो एक परंपरा बन गयी है। पिछले साल 'न्यू देहली टाइम्स' को फिल्मोत्सव में शामिल करने के बाद न दिखाने की घोषणा ने विवाद को जन्म दिया था, तो इस साल त्रिवेंद्रम में संपन्न फिल्मोत्सव भी कई वजहों से विवाद से परे नहीं रह सका। इस फिल्मोत्सव में उठे विवादों पर एक रपट :

पिछले दो महीनों तक आशंकाओं, ऊहापोहों, अंतर्विरोधों और कशमकश के बाद जिस तरह ८ वां गैर-प्रतियोगी फिल्मोत्सव त्रिवेंद्रम में संपन्न हुआ, उसमें पिछले साल हैदराबाद में हुए फिल्मोत्सव जैसी न तो गर्मी थी और न ही उत्साह। हैदराबाद का फिल्मोत्सव वहां के मुख्यमंत्री एन०टी० रामाराव के अतिउत्साह के कारण शाही आयोजन बन गया था। एशिया के किसी भी देश में इतना भव्य आयोजन कभी नहीं हुआ था, त्रिवेंद्रम में भी नहीं, जबकि १९८८ के इस फिल्मोत्सव के साथ दो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी थीं—यह वर्ष मलयाली सिनेमा का स्वर्ण जयंती वर्ष है, साथ ही फिल्म इंस्टीट्यूट पूना का रजत जयंती वर्ष भी। फिल्म इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा फिल्म स्नातक मलयाली सिनेमा को दिये हैं। कलाकार और निर्देशक से लेकर कैमरामैन, संपादक तथा दूसरे तकनीशियन भी।

इस वर्ष फिल्मोत्सव के लिए त्रिवेंद्रम का चुनाव इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया था। दरअसल, त्रिवेंद्रम में यह आयोजन और भी पहले हो जाना चाहिए था, बंगलौर या हैदराबाद से भी पहले। मलयाली सिनेमा ने भारतीय सिनेमा के दिशा निर्धारण में जितना योगदान किया है उतना तमिल, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा ने नहीं। कला फिल्मों के साथ-साथ व्यावसायिक और सेक्स प्रधान फिल्मों में क्रांतिकारी भूमिका मलयाली फिल्मों ने ही निभायी है। साथ ही व्यवस्था, कानून और भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुलकर बोलने की हिम्मत [illegible] उसी ने दिखलायी।

केरल में साक्षरता ७० प्रतिशत होने के कारण वहां बननेवाली फिल्मों में कलात्मकता, सुरुचि संपन्नता एवं सौंदर्यबोध के साथ कथावस्तु, नयी सोच, कल्पनाशीलता का प्रभाव दिखलायी पड़ा, जिसकी नकल अन्य भाषाओं की फिल्मों ने हमेशा की। केरल की इसी विशेषता और वहां के दर्शकों की इसी रुचि-संपन्नता के कारण इस ८ वें गैर-प्रतियोगी फिल्मोत्सव में सेक्स-प्रधान फिल्मों

मुकाबले कलात्मक फिल्मों को देखने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं थी। इस बार, हमेशा की तरह फिल्मोत्सव का प्रतीक चिह्न दिल्ली में बनवाने के बजाय इसकी जिम्मेदारी केरल के प्रख्यात कलाकार श्री नंबूदिरी पर सौंपी गयी।

विरोध और विवाद: इस फिल्मोत्सव को जब त्रिवेंद्रम में कराने का निर्णय फिल्मोत्सव निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम, सूचना मंत्रालय ने लिया, तो दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने इसका हार्दिक स्वागत किया था। लेकिन जैसे-जैसे फिल्मोत्सव का दिन निकट आने लगा, विरोध बढ़ता गया। इस बीच केरल फिल्म इंडस्ट्री में चल रही लंबी हड़ताल ने भी फिल्मोत्सव के सामने कम संकट नहीं पैदा किये, क्योंकि फिल्म निर्माताओं, वितरकों-प्रदर्शकों से लेकर सिनेमाघरों के दरवाजे तक हड़ताल के कारण बंद थे।

विवाद का मुख्य कारण था फिल्मोत्सव में दक्षिण भारतीय फिल्मों को समुचित प्रतिनिधित्व न मिलना। फिल्मकारों की शिकायत थी कि सिर्फ छह मलयाली फिल्मों को ही भारतीय पैनोरमा में शामिल किया गया, जबकि मलयाली फिल्मों का यह स्वर्ण जयंती वर्ष है। वे चाहते थे कि गैर-प्रतियोगी फिल्मोत्सव के समानांतर मलयाली फिल्मों का एक अलग प्रखंड कर १५ दिनों तक लगातार चुनिंदा मलयाली फिल्में दिखलायी जायें। कुछ निर्माताओं ने यह भी सुझाव रखा था कि एक थियेटर में सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्में ही प्रदर्शित की जायें। इनमें प्रतिदिन तीन मलयाली तथा दो तमिल, तेलुगु और कन्नड फिल्में (सर्वश्रेष्ठता के प्रतिशत के आधार पर) दिखलायी जायें। मलयाली फिल्म निर्माताओं के आक्रोश का दूसरा कारण यह था कि फिल्मोत्सव में दिखलायी जानेवाली फिल्मों के चुनाव के लिए गठित चयन समिति में एक भी सदस्य मलयाली फिल्म उद्योग से नहीं लिया गया था।

मलयाली फिल्मों के प्रख्यात निर्माता-निर्देशक एम०टी० वासुदेव नायर का कहना था, "उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन जब त्रिवेंद्रम में फिल्मोत्सव मनाया जा रहा है और मलयाली फिल्मों का स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो कम-से-कम मलयाली फिल्मों के सम्मान और केरलियों की भावनाओं का आदर रखने के लिए तो ऐसा किया ही जाना चाहिए था।" एक अन्य फिल्म निर्देशक के०जी० जार्ज भी इस रवैये से क्षुब्ध थे, विशेषकर समारोह के उद्घाटनकर्ता के नाम को लेकर। मलयाली कला फिल्मों के जाने-माने फिल्मकार जी० अरविंदन का कहना था, "जब सत्यजित राय का नाम फिल्मोत्सव के उद्घाटन के लिए घोषित किया गया, तो हमें दुख और खुशी दोनों हुई। सत्यजित राय महान फिल्मकार हैं। मलयालम में उनकी टक्कर का न सही, परंतु कई ऐसे महान फिल्मकार हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नयी दिशा दी है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है, उद्घाटन उनसे कराना चाहिए।" जी० अरविंदन की बातों का समर्थन लगभग हर मलयाली फिल्मकार ने किया। इस विवाद को देखते हुए फिल्मकार सत्यजित राय ने उद्घाटन करने से मना कर दिया। फिल्मोत्सव निदेशालय ने कलकत्ता और बंबई फिल्म इडस्ट्री के कई जाने-माने फिल्मकारों से बात की, लेकिन सभी ने नामंजूर कर दिया। मृणाल सेन को उद्घाटन के लिए, फिल्मोत्सव से सिर्फ चार दिन पहले राजी करा पाये। इसकी भी तीव्र प्रतिक्रिया मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में हुई, लेकिन उन्होंने खामोश रह कर ठीक फिल्मोत्सव के दौरान श्रेष्ठतम मलयाली फिल्मों का अलग प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

मलयाली फिल्मकारों की तरह तमिल-तेलुगु-कन्नड़ फिल्म उद्योग के लोग भी सख्त नाराज थे और उन्होंने फिल्मोत्सव का बहिष्कार करने की धमकी दे दी थी। फिल्मोत्सव अधिकारियों के कई दल उन्हें समझाने-बुझाने के लिए मद्रास गये। अंततः एक वर्ग फिल्मकार रामानुजम के नेतृत्व में फिल्मोत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हो गया और शेष ने अंतिम समय बहिष्कार की धमकी वापस ले ली, लेकिन अपनी फिल्मों की शूटिंग फिल्मोत्सव तिथि के दौरान ही तय कर दी, फलतः शूटिंग में व्यस्त बहुत से कलाकार फिल्मोत्सव में शामिल नहीं हो सके। यही स्थिति बंबई के नाखुश सिनेमा उद्योग की भी थी। तमिल-तेलुगु फिल्मों के हिट डायरेक्टर के० बालचंद्र ने 'माया' को बतलाया, "विरोध की बात जायज थी। विरोध तब किया गया जब उन्हें पता चला कि तमिल-तेलुगु में बनी ३०० में से एक भी फिल्म का चयन नहीं किया गया। १९८७ की सर्वाधिक बहुचर्चित फिल्म 'नायकन' भी उन्हें नहीं जंची, जबकि 'नायकन' आस्कर पुरस्कारों के लिए मनोनीत की गयी है और अब हिंदी (अभिनेता फीरोज खान द्वारा) तथा दूसरी भाषाओं में इसका रीमेक हो रहा है।"

बर्नाडो बर्टोलूची (इटली) की फिल्म 'द लास्ट एम्परर' का दृश्य

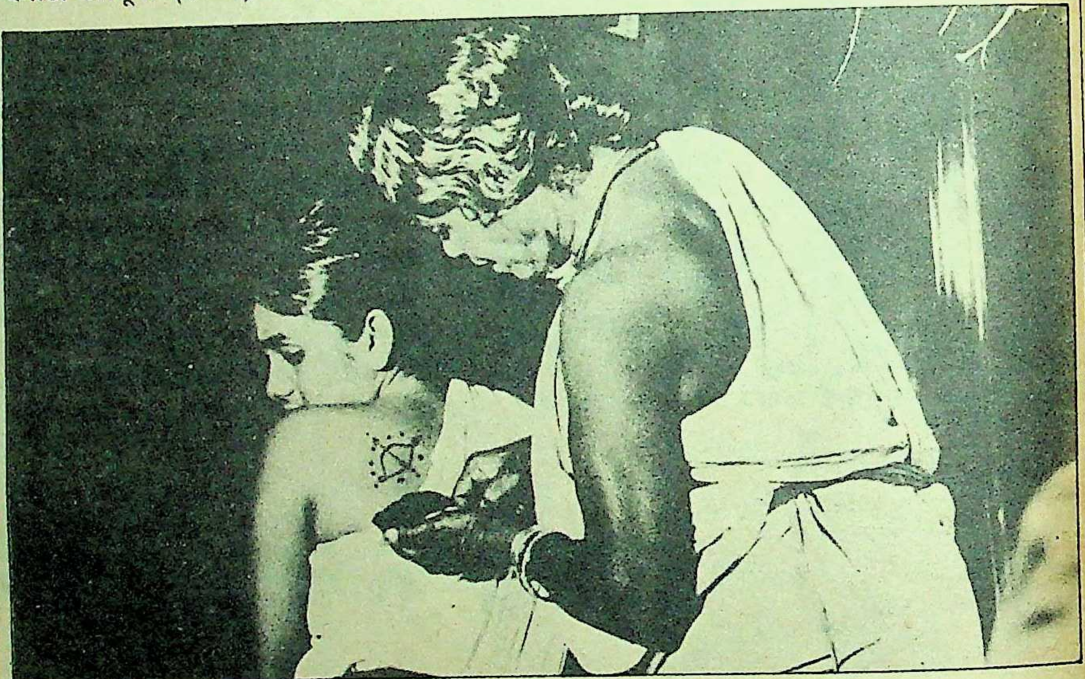

मलयाली फिल्म 'मालामुकाली दिवम' का एक दृश्य

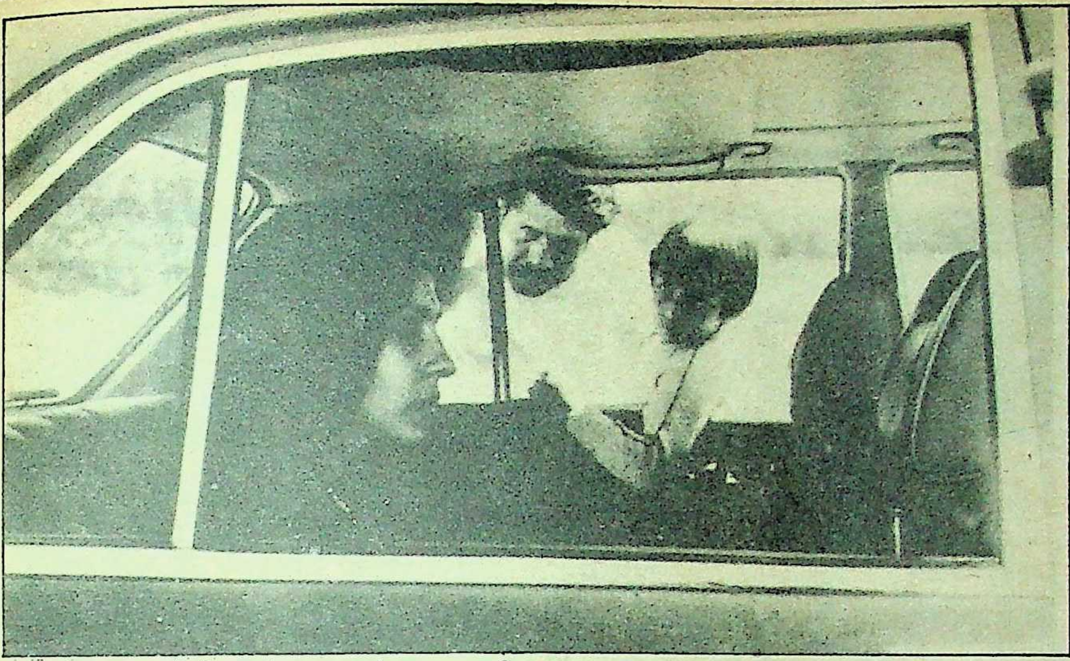

एक और मलयाली फिल्म 'पुरुशरथान' का भावपूर्ण दृश्य

तपन सिन्हा की फिल्म 'आज का राबिन हुड' का एक दृश्य

दक्षिण भारतीय फिल्मकारों की सबसे प्रमुख शिकायत थी, "त्रिवेंद्रम में फिल्मोत्सव आयोजित करने का फैसला सरकार ने एकतरफा लिया था, हमें न तो विश्वास में लिया गया और न ही हमसे इस बारे में कोई बातचीत की गयी। हम इसे और भी शानदार बनाते, हैदराबाद के फिल्मोत्सव से भी शानदार और कार्लोवीवेरी, पेरिस या रूस में होने वाले फिल्मोत्सवों के टक्कर की। यह सिर्फ सरकारी तथा नव-सिनेमाकारों का आंदोलन बन कर रह गया है।" मजेदार बात तो यह थी कि राष्ट्रीय वित्त निगम की प्रबंध निदेशिका श्रीमती उर्मिला गुप्ता बड़े नाटकीय ढंग से दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के विरोध और बहिष्कार की धमकी से अपने को अनजान बतलाती रहीं और सत्यजित राय द्वारा उद्घाटन करने से इनकार करने की खबर की अंतिम समय तक पुष्टि करने से हिचकती रहीं।

केरल के मुख्यमंत्री ई०के० नयनार का फिल्म इंडस्ट्री से नाता नहीं था, इसलिए उन्होंने आयोजन की सारी जिम्मेदारी केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन को सौंप दी। फलतः सरकारी आयोजन का हश्र सरकारी ढंग से उजागर हुआ।

कैसी-कैसी फिल्में ? : ८ वें फिल्मोत्सव के लिए १५० से अधिक विदेशी फीचर फिल्मों तथा ५० लघु फिल्मों का चुनाव चयन समिति ने किया। चूंकि गैर-प्रतियोगी फिल्मोत्सवों में विश्व की सर्वश्रेष्ठ और चुनी फिल्में ही दिखलायी जाती हैं, इसलिए इस बार भी कई प्रख्यात फिल्में दर्शकों को देखने को मिलीं। इनमें से मुख्य खंड में अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा; यूनान, हंगरी, कोरिया गणतंत्र, ईरान, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस की ७५ फिल्में थीं। इनमें से अधिकांश फिल्में या तो अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में प्रदर्शित हो चुकी थीं या अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थीं। भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित १८ फीचर फिल्मों में से छह मलयाली थीं। इसी प्रखंड में २१ लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गयीं। मुख्य धारा के तहत ३५ फीचर एवं २१ लघु फिल्में चुनी गयी थीं। फिल्म इंस्टीट्यूट पूना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा बनायी गयी श्रेष्ठतम फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक विशेष आयोजन किया गया था। 'डाक्युमेंट्री ८८' में प्रदर्शन के लिए इस बार चुने गये 'एपार्थाइड' तथा 'न्यूक्लीयर' विषयों पर ही वृत्त एवं लघु फिल्मों का संग्रह समूचे विश्व से किया गया था। इनमें 'द डार्क सर्किल' (अमरीका) तथा 'द ग्रेट' (स्वीडन) अपने कथ्य के लिए १९८७ में काफी चर्चित हो चुकी हैं और इनके वीडियो टेप ब्लैक में बिके थे।

हानि-लाभ : वर्तमान सूखे के संकट को ध्यान में रखते हुए इस फिल्मोत्सव को रद्द कर देने की मांग कांग्रेस एवं गैर-कांग्रेसी दोनों हलकों से उठी थी, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री ई०के० नयनार तथा सूचना प्रसारण मंत्री अजीत पांजा किसी भी शर्त पर इसे आयोजित करना चाहते थे। दोनों के अनुसार 'फिल्मोत्सव में होने वाला खर्च ऐसी धनराशि नहीं थी कि इससे सूखे की भयावहता को रोका जा सकता।' फिर फिल्मोत्सव कला, परंपरा और संस्कृति का संगम भी है जो भारतीय फिल्मकारों को विश्व सिनेमा की ताजगी का एक नया अहसास कराता है। राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम की प्रबंध निदेशक मालती तांबे वैद्य के अनुसार, "इसका एक मुख्य व्यावसायिक मकसद भी है, जिसका आर्थिक लाभ भी हम उठाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो खरीददार के अभाव में डिब्बे या लैब में बंद पड़ी रह जाती हैं, फिल्मोत्सव में बिक जाती हैं। बेहतरीन फिल्मों के आयात एवं अपनी फिल्मों के निर्यात के लिए भला इससे अच्छा मौका कब मिलता है। इधर पश्चिमी देशों के खरीददारों की रुचि भारतीय फिल्मों में तेजी से बढ़ी है। फिल्मों के अधिकाधिक निर्यात से हम अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। फिर आप ऐसे आयोजनों को हानि-लाभ के तराजू में भला कैसे तौल सकते हैं ?"

फिल्मोत्सव निदेशालय अभी तक राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम के छतरी तले फिल्मोत्सवों का आयोजन करता रहा है, लेकिन आगे से उसे स्वायत्तता देकर सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत कर देने की योजना है। त्रिवेंद्रम फिल्मोत्सव के परिणाम को देखने के बाद इस योजना को क्रियान्वित किया जाना था। यदि ऐसा हो गया, तो निदेशालय को राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम के साथ अंतिम समय तक होने वाली कशमकश और ऊहापोह से मुक्ति मिल जायेगी। निगम फिल्मोत्सव में हिंसा और सेक्स प्रधान ऐसी फिल्में लाना चाहता है, जिनका सौदा आसानी से हो सके ताकि बिकने पर उसका कमीशन निगम को मिल सके, जबकि निदेशालय ऐसी फिल्में लाना चाहता है जिससे फिल्मोत्सव की अंतरराष्ट्रीय गरिमा बढ़ सके। **—विध्येंदु गुहा और बंबई ब्यूरो**

'जिंदगी' सीरियल

भारतीय नारी के हालात का सच्चा आइना

इधर 'दूरदर्शन' ने विविध वर्गों की नारियों की विभिन्न स्थितियों, उनके कार्यकलापों, उनकी अस्मिता, स्वतंत्रता और पुरुषों की मदद के बिना अपने जीवन को सफल बनाने को केंद्र में रखकर कई सीरियल प्रदर्शित किये हैं। इस संदर्भ में साहित्यिक कृतियों को भी आधार बनाया है। 'जिंदगी' अमृता प्रीतम के उपन्यासों पर आधारित सीरियल है। इसकी प्रस्तुति में पटकथा लेखक और निर्देशक वेद राही कितने सफल रहे हैं?

अस्मिता का प्रश्न : परीक्षित साहनी और शर्मिला टैगोर

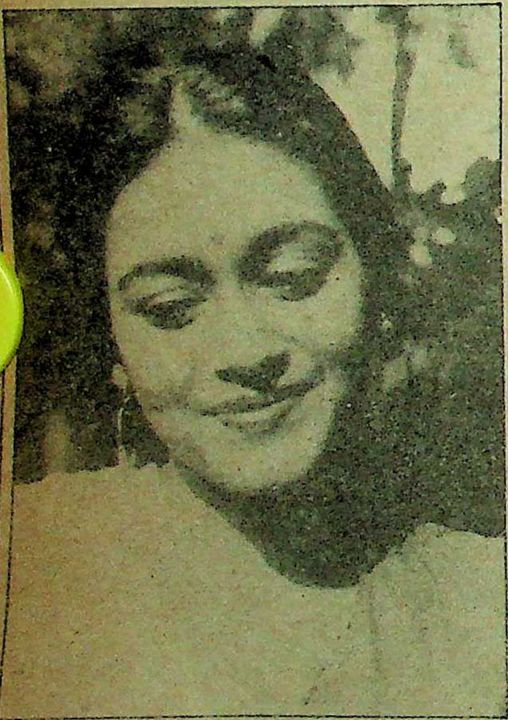

जरूरी नहीं पुरुष का संरक्षण : सुप्रिया पाठक

इधर दूरदर्शन पर जितने सीरियल दिखाये जा रहे हैं, उनके जखीरे में एक ही सीरियल लोगों को बांध सका है, वह है—'जिंदगी'। इसका मुख्य कारण है पटकथा का अमृता प्रीतम के उपन्यासों के चरित्रों और घटनाओं पर आधारित होना। पटकथा लेखक है वेद राही, जो मूलतः कथाकार है, और जिन्हें अपनी संवेदनशील कहानियों के लिए काफी लोकप्रियता और सम्मान मिल चुका है। इसके

साक्षात्कार/ वेद राही

स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व का होना जरूरी है

माया : आप फिल्म जगत में सशक्त संवाद लेखन के लिए मशहूर रहे हैं। 'प्रेम पर्वत', 'काली घटा' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया, फिर फिल्म के बड़े परदे से टी०वी० पर आने का खयाल कैसे आ गया?

वेद राही : आपकी बात एक हद तक ठीक है। मेरी लिखी हुई फिल्में ('बेईमान', 'सन्यासी', 'चरस', 'बेजुबान', 'आंखें', 'पवित्र पापी', 'ये रात फिर न आयेगी', 'बाप-बेटी', 'प्रेम पर्वत' आदि) बाक्स आफिस पर हिट रही हैं। दरअसल मैं फिल्मकार के बजाय कथाकार के रूप में ज्यादा मशहूर रहा हूं। मुझे अपने एक कथा-संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी १९८३ में मिल चुका है। 'कथासागर' वालों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो साहित्यकार भी हो साथ ही फिल्मों से भी जुड़ा हो। किसी ने उन्हें मेरा नाम सुझाया। 'कथासागर' काफी कठिन होम वर्क था। विश्व की हजारों कहानियों में २७ सर्वश्रेष्ठ कहानियों का चुनाव आसान बात नहीं थी। फिर उन कहानियों का भारतीयकरण करना और भी कठिन था। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन उसका मुआवजा तब मिल गया, जब लोगों ने उसे सराहा।

माया : 'जिंदगी' में आपने संवाद और पटकथा भी लिखी है, साथ ही निर्देशन भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ करने में दिक्कत महसूस नहीं होती?

वेद राही : नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में रहकर कई फिल्मों का निर्माण, निर्देशन व लेखन करके अनुभव प्राप्त कर चुका हूं। यह तो और भी अच्छी बात है कि मैं स्वयं जो लिखता हूं, उसे अपनी कल्पना के अनुसार फिल्मा लेता हूं। इस तरह सारा काम और भी आसान हो जाता है, कोई दिक्कत महसूस नहीं करता मैं।

माया : 'जिंदगी' अमृता प्रीतम के उपन्यासों पर आधारित सीरियल है, उपन्यासों का क्या मतलब?

अलावा वेद राही पिछले दो दशकों से फिल्मों से बखूबी जुड़े रहे। एक तरफ उन्होंने सुपरहिट कार्मशियल फिल्मों की पटकथाएं एवं संवाद लिखे, तो दूसरी तरफ कई फिल्मों (प्रेम पर्वत, दरार, काली घटा, नादानियां आदि) का निर्देशन भी किया। वेद राही फिल्मों के साथ-साथ सक्रिय लेखन से जुड़े रहे, इसीलिए कमलेश्वर या डा० राही मासूम रज़ा की तरह सिर्फ फिल्मों के ही होकर नहीं रह गये। वह सफलता-असफलताओं से जूझते हुए अपने सीमित दायरे में रहकर भी प्रयोगधर्मी बने रहे। फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ के पुत्र प्रेम किशन ने जब फिल्म अभिनय (प्रथम फिल्म : 'दुल्हन वही जो पिया मन भाये') में हाथ मारने के बाद असफल हो विज्ञापन फिल्मों तथा दूरदर्शन की ओर रुख किया, तो विश्व की श्रेष्ठतम कहानियों पर आधारित 'कथासागर' सीरियल बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। इन कहानियों के चुनाव और उनकी पटकथा तैयार करने के लिए नजर दौड़ायी, तो उन्हें सर्वाधिक योग्य शख्स सिर्फ वेद राही दिखलायी पड़े। इसीलिए यश चोपड़ा जैसे सशक्त और प्रभावशाली निर्माता-निर्देशक की देखरेख में बनी कहानियों पर ही आधारित 'खजाना' तथा सत्यजित रे और मृणाल सेन की प्रख्यात कहानियों पर आधारित सीरियलों के मुकाबले 'कथासागर' (सिर्फ) लेखन की दृष्टि से बाजी मार ले गया और इसका सारा श्रेय वेद राही को गया।

साहित्यिक कृतियों पर सीरियल या फिल्म बनाना सर्वाधिक कठिन काम है, विशेषकर हिंदी में। एक तरफ मूल रचनाकार अपनी कृति में परिवर्तन न करने की जिद्द पर अड़ा रहता है, दूसरी तरफ फिल्म या सीरियल निर्माता 'विजुअल मीडिया' होने के कारण (कभी-कभी दखलंदाजी की हद तक) परिवर्तन करना जरूरी समझता है। यही कारण था कि निर्माता-निर्देशक बासु भट्टाचार्य की अमृता प्रीतम की एक कहानी पर बनी फिल्म 'डाकू' सिर के ऊपर से निकल गयी। न उसे प्रबुद्ध दर्शकों ने सराहा और न ही आम दर्शकों ने। "इस बारे में मैं भाग्यशाली रहा कि अमृताजी (अमृता प्रीतम) ने मुझे पूरी छूट दे दी।" 'जिदगी' सीरियलकार वेद राही ने 'माया' को बतलाया, "इसे छूट नहीं बल्कि आजादी कहूंगा जो अगर उन्होंने नहीं दी होती, तो उनके उपन्यासों से पात्रों और घटनाओं का मैं चयन कर अलग पटकथा कैसे तैयार करता ?"

'जिदगी' की सफलता वेद राही की सफलता है। शर्मिला ठाकुर, सुप्रिया पाठक तथा सदाशिवराव अमरापुरकर, बीना और बेंजामिन गिलानी ने प्रभावशाली अभिनय किया है।

—बंबई ब्यूरो, महादेव शर्मा

वेद राही : मुझे यह कहते हुए फख्र भी महसूस हो रहा है और यह सोच कर दुःसाहस भी अनुभव करता हूं कि अमृता प्रीतम जैसी महान लेखिका की रचनाओं पर सीरियल लिखने व बनाने का मौका मिला, संभवतः सीरियल-निर्माण की दुनिया में यह पहला अवसर है जबकि एक लेखिका के कई उपन्यासों की कथा-भूमि और उनके चरित्रों, घटनाओं को लेकर अलग से एक मूल-कथा के रूप में पिरोया गया हो। मेरे विचार से ऐसा पहले नहीं हुआ। उनके एक उपन्यास से नायक, तो दूसरे से नायिका और तीसरे, चौथे, पांचवें उपन्यासों से विभिन्न पात्रों का चयन किया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमृताजी ने इसकी इजाजत दे दी, जब कि खासतौर पर लेखक अपनी रचना में थोड़ा भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते। अमृताजी ने 'जिदगी' की पटकथा देखकर मुझसे कहा था, "वेद, सचमुच तुमने अद्भुत काम किया है, यह तो मैं भी नहीं कर सकती थी..."

माया : आपने 'कथासागर' का निर्देशन क्यों नहीं किया था? 'जिदगी' का ही क्यों किया?

वेद राही : निर्माता प्रेम किशन ने कहा कि 'जिदगी' का निर्देशन भी आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूं। 'कथासागर' के कई निर्देशक थे, लेकिन लेखक अकेला मैं ही था—सभी २७ एपीसोडों का। फिर अमृताजी भी चाहती थीं कि जब मैं ही 'जिदगी' का लेखन कर रहा हूं, तो निर्देशन भी मैं ही करूं, ताकि जो लिखूं उसे कैमरे में दर्ज कर सकूं। मैं भी चाहता था कि कैरेक्टर को विशाल कैनवास और घटनाओं को अपने ढंग से ढाल सकूं, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि यह पहला सीरियल है, जिसे हम मल्टीस्टार सीरियल कह सकते हैं। 'जिदगी' में शर्मिला टैगोर, परीक्षित साहनी, सुप्रिया पाठक, सदाशिव अमरापुरकर, बेंजामिन गिलानी, निवेदिता जोशी, बीना जैसे नामी-गिरामी फिल्म स्टारों ने काम किया है।

माया : 'जिदगी' के माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं?

वेद राही : भारतीय नारी को आज के हालात का किस तरह सामना करना चाहिए, विशेषकर मानसिक रूप से अपने को किस तरह से आत्म-निर्भर बनाना चाहिए, मैं इसे दर्शाना चाहता था। भारतीय संस्कारों का जामा पहने हुए भी औरत क्या पुरुष के बिना अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है या स्त्री जिदगी में पुरुष अथवा पति के रिश्ते के बिना भी जी सकती है या नहीं, मेरे विचार से वह दोनों ही परिस्थितियों में जी सकती है। मनचाहा पति मिलने पर भी स्त्री को स्वाभिमान के साथ जीना जरूरी है। यदि उसे 'स्व' के बलिदान के साथ सुख और संपन्नता मिलती है, तो भला उसकी जिदगी में इसकी क्या कीमत ? ऐसे पुरुष के साथ जीकर भी भला क्या फायदा। स्वतंत्र अस्तित्व का होना जरूरी है। इसी विषय को हमने कहानी का मूल विषय बनाया है।

—महादेव शर्मा

साक्षात्कार/ प्रेम किशन

मूड नहीं है अभिनय करने का

माया : आपने तो अपना कैरियर अभिनय से शुरू किया था, सीरियलों की तरफ कैसे मुड़ गये?

प्रेम किशन : यह है न मजेदार बात कि मेरी पहली ही फिल्म 'दुल्हन वही जो पिया मन भाये' बाक्स आफिस पर सुपर हिट हुई थी, उसके बाद मैंने कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन खास परिणाम सामने नहीं आया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इधर सीरियलों का दौर शुरू हुआ, तो मैं इससे जुड़ गया।

माया : आप अपने सीरियलों में भी तो काम कर सकते थे, क्यों नहीं किया?

प्रेम किशन : फिलहाल तो मेरा मूड नहीं है अभिनय करने का। जब कभी महसूस करूंगा, तो अभिनय भी शुरू कर दूंगा। फिलहाल मेरी आनेवाली एक फिल्म 'साजिश' है जिसमें मेरा अहम किरदार है।

माया : आप सीरियल के बजाय फीचर फिल्में भी तो बना सकते थे जबकि आपका सीधा संबंध राज कपूर बैनर से रहा है? वह आपके सगे मामा हैं।

प्रेम किशन : देखिए, फीचर फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। एक तो लाखों-करोड़ों रुपए लग जाते हैं, फिर अगर खुदा नखास्ता कहीं फिल्म फ्लाप हो जाये, तो सीरियल बनाने काबिल भी नहीं रहते, दूसरी बात यह है कि फीचर फिल्म के लिए हमें कोई मनचाहा सब्जेक्ट भी नहीं मिला। जब भी कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, तो फीचर फिल्म भी बनाऊंगा। रही बात राज साहब के बैनर या उनसे रिश्तेदारी की, तो हम लोग कभी किसी के सहारे पर निर्भर नही रहते—खुद न तो राज साहब रहे न उनके कोई बेटे। हर कोई अपने पांव पर खुद खड़ा हुआ।

माया : क्या आपके दोनों सीरियलों में पापाजी (प्रेमनाथ) का भी किसी रूप में सहयोग रहा है?

प्रेम किशन : वैसे तो पापा का ही आशीर्वाद है लेकिन वह हमारे काम में हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अब वह पूर्णतः विश्राम कर रहे हैं।

—महादेव शर्मा

बढ़ती जनसंख्या, घटता उत्पादन

जिस अनुपात में जनसंख्या-वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में हम पैदावार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हरित-क्रांति के बावजूद खाद्यान्न की पैदावार में उत्तरोत्तर कमी क्यों होती जा रही है?

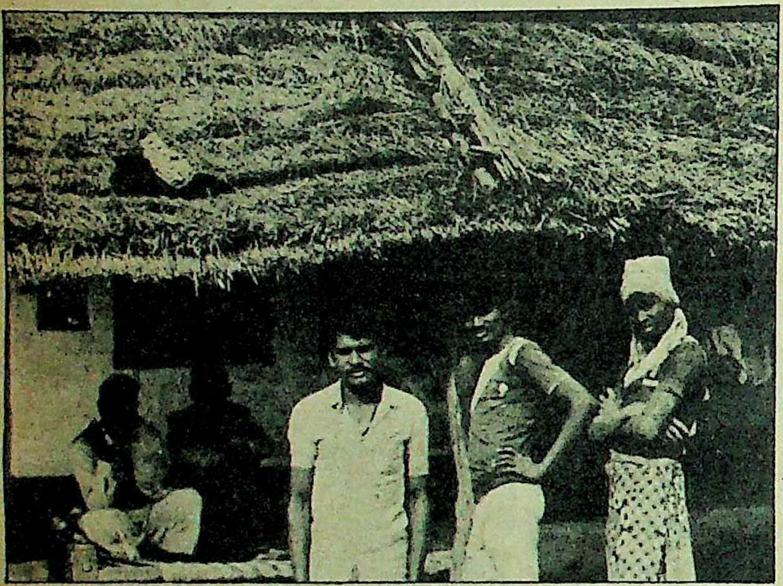
साधनों के अभाव में बेकार किसान

गांवों की कीमत पर फलते शहर

अगर देश में १९८४-८५ के कुल उत्पादन को सभी देशवासियों में बराबर-बराबर बांट दिया जाये, तो १९८८ में हर आदमी के हिस्से आयेगा १८३ ग्राम चावल, १३७ ग्राम गेहूं, ४० ग्राम दाल तथा ९८ ग्राम ज्वार-बाजरा जैसे मोटे अन्न। चीनी और खाने के तेलों के लिए भी ऐसा ही हिसाब लगाइये। आज हर आदमी को करीब ६३ ग्राम चीनी और २० ग्राम खाने का तेल मिलेगा। उल्लेखनीय है कि १९८४-८५ में रिकार्ड पैदावार हुई थी।

कई साल पहले गेहूं, चावल और मोटें अनाजों का हिस्सा तो थोड़ा कम होता, पर दाल और खाने के तेल का हिस्सा ज्यादा होता। दूसरे शब्दों में देश में गेहूं, धान और मोटे अनाजों के उत्पादन में जनसंख्या के अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि तेलहन और दलहन में गिरावट आयी है। जिन अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई हैं, उनकी प्रति एकड़ पैदावार भी बढ़ी है। साथ ही अनेक कारणों से पिछले कई वर्षों से अधिक से अधिक जमीन पर अनाज उपजाने का चलन बढ़ा है। साथ ही अन्य जिसों की खेती कम हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ०प्र० के लिए गेहूं सबसे प्रिय फसल बन गयी है। इस इलाके को देश का गेहूं वाला क्षेत्र कहा भी जाने लगा है।

अब यह स्थिति आ गयी है कि गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार में पहले जितनी रफ्तार से वृद्धि नहीं हो सकती। दरअसल कुछ जिलों में तो अब यह वृद्धि रुक ही गयी है। दूसरी ओर पहले जितनी फसल होने के लिए ही खाद, बीज तथा कीटनाशक पर लागत कम नहीं हो सकती। उलटे लागत में वृद्धि ही होनी है। कम-से-कम रासायनिक खादों पर तो यह बात लागू होती ही है। खाद की कीमत बढ़ानी ही होगी या फिर सरकार को किसानों की इस पर दी जाने वाली सबसिडी बढ़ानी होगी। कर राजस्व में सबसिडी देना अब बहुत मुश्किल है। सरकार के पास पैसे की भयंकर कमी है इसलिए वह और नोट छापकर या लोगों से उधार लेकर अपना खर्च चला रही है।

पंपों की बिजली, कीटनाशक और खादों की कीमत जब किसान अधिक देगा, तो गेहूं उत्पादन पर लागत राशि बढ़ेगी ही, पर उसे उसके उत्पादन के लिए सरकार जो कीमत देती है या जिस कीमत पर वह उसे खुले बाजार में बेचता है, इसमें उतनी वृद्धि नहीं हो रही। परिणामस्वरूप उसकी आय घटती जा रही है। कई बार तो वह पिछले वर्ष से अधिक पैदावार के बावजूद घाटे में रहता है।

इसके साथ ही मुद्रास्फीति की मार उस पर भी उतनी ही पड़ती है, जितनी किसी अन्य पर। इस प्रकार उसकी वास्तविक आय तेजी से गिरती जा रही है और इतनी रफ्तार से उसकी खेती की आमदनी नहीं हो पा रही है। वह दोनों ही ओर से पिट रहा है। लागत राशि और बिक्री की कीमत के बीच फासला कम होते जाने से उसका मुनाफा गिरता जा रहा है। मुद्रास्फीति के कारण भी उसकी वास्तविक आय गिर रही है। इसलिए अपनी जरूरत की चीजों के खरीदने या अनाज उगाने के लिए लगाने वाले शुद्ध खर्च में कमी होती जाती है।

अगर यह हालत देश के तीन चौथाई किसानों की है, तो इसका अर्थ हुआ कि अधिकांश किसान आज उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं रह गये हैं। इनमें अपनी जमीन पर या बटाई की जमीन पर खेती करने वाले भी शामिल हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता।

हरित क्रांति: छठे दशक के उत्तरार्द्ध में शुरू होकर सातवें दशक के उत्तरार्द्ध तक धूम मचाये रखने वाली 'हरित क्रांति' का क्या हुआ? कुछ इलाकों और फसलों में प्रति एकड़ पैदावार में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई। इन इलाकों और फसलों के लिए पानी, खाद, कीटनाशक और अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराये गये। सबसे अधिक अच्छी स्थिति में गेहूं रहा। देश के कुछ जिलों में धान की पैदावार भी उसी तेजी से बढ़ी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों के कुछ जिलों में धान की पैदावार तेजी से बढ़ी। कुल मिलाकर देश की जितनी जमीन पर खेती होती है, उसमें तेज विकास करने वाली फसलों वाली जमीन का हिस्सा ३० फीसदी था।

शेष जमीन पर पैदावार में वृद्धि की रफ्तार बहुत कम रही। इसके साथ ही गेहूं को छोड़कर अन्य अनाजों के उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार काफी कम रही। इन इलाकों में सिचाई की सुविधा, खाद की खपत भी कम रही। जिस तरह से गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्में आयीं, उस तरह की किस्में अन्य

फसलों के लिए नहीं आयीं और इस सबका परिणाम हर किसी के सामने है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अनाज तभी मिल सकता है, जब प्रति एकड़ धान, दलहन और अन्य मोटे अनाजों की पैदावार भी तेजी से बढ़े। जमीन को इतना उपजाऊ बनाने के लिए उसमें डाली जाने वाली चीजों की मात्रा भी बढ़ायी जानी चाहिए। साथ ही अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध होने चाहिए। अनाज की पैदावार बढ़ाने का दूसरा रास्ता और अधिक जमीन पर फसलें उगाना है। इसके लिए दूसरी जिंसों की पैदावार बंद करना होगा। पर इसका कई तरह से बुरा असर होगा। देश में अभी ही खाने के तेलों का संकट है, यह और बढ़ जायेगा और इसका आयात बढ़ाना होगा। इसलिए सभी तरह से हिसाब लगाने के बाद भी यही लगता है कि अगर कोई चमत्कार न हो जाये, तो देश अनाज की कमी के दौर में फंसने जा रहा है। ऐसे चमत्कार को लाने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। व्यापक सिंचाई की सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी। ऐसा पर्याप्त नहरों के निर्माण या भारी तादाद में पंपों के उपलब्ध होने से संभव होगा। इसके साथ ही किसान के पास खाद, बीज तथा कीटनाशक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इसके लिए उसे कर्ज चाहिए जो सरकार निकट भविष्य में देने की स्थिति में नहीं है। तीसरे, जिन इलाकों में सिंचाई सुविधा नहीं दी जा सकती, वहां ऐसी फसलें उगायी जानी चाहिए जो बिना बहुत अधिक पानी के भी पैदा हो सकें। इसके साथ ही खेती में लगने वाली चीजों की कीमत बहुत अधिक नहीं बढ़नी चाहिए या फिर किसान को उसकी पैदावार की अधिक-से-अधिक कीमत मिलनी चाहिए।

यह कहां तक संभव होगा और साथ ही मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसका हिसाब सहज ही लगाया जा सकता है। सारी आशावादिता के बावजूद ये सभी चीजें हो नहीं सकतीं और अनाज के उत्पादन में वृद्धि-दर जनसंख्या में वृद्धि-दर से कम रहेगी। अब तो हरित क्रांति में भी कोई हरियाली नहीं रह गयी है। यह अपने अवसान पर पहुच चुकी है, कम-से-कम अगले कुछ समय के लिए तो निश्चित ही।

—कुमारेश चक्रवर्ती

घटती आय, बढ़ती कीमतें

जिन लोगों को शहरी इलाकों में राशन की दुकानों के आगे की लंबी कतारों, प्रतिबंधित इलाकों में अनाज की तस्करी, अनाज की कालाबाजारी और किल्लत की याद होगी, वे इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अनाज की कमी होने या आयात की नौबत आने पर यही सब कुछ होता है। तब सरकार को किसानों का अनाज खरीदने के लिए लेवी लगानी पड़ती है। इसके बिना व्यापारियों के हाथ में सारा खेल चला जाता है और अनाज की कीमत आसमान छूने लगती है। किसानों से लेवी लिये बिना सरकार राशन की दुकानों में सस्ते दर पर बेचने के लिए अनाज नहीं जुटा सकती। खुले बाजार में तो अनाज की कीमतें काफी चढ़ गयी होती हैं।

पचास और साठ के दशक में ऐसी ही मुश्किलें आ पड़ी थीं। देश में अनाज का उत्पादन जरूरत से काफी कम होता था, इसलिए आयात जरूरी हो गया था। कुछ वर्षों में तो अनाज के आयात का बिल भारत द्वारा लिये जाने वाले विदेशी मुद्रा के भुगतान का ४१ फीसदी तक पहुंच गया था। फिर ऐसा भी समय आ गया कि अनाज के लिए डालर का भुगतान भी होने लगा। इसलिए अमरीका से एक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार वहां से आनेवाले अनाज का भुगतान रुपए में ही करना था लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि भारत स्थित अमरीकी दूतावास में सैकड़ों करोड़ रुपए का अंबार लग गया और यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। अगर किसी दूतावास के पास काफी पैसा रहे, तो वह इसका मनमाना इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कुछ कार्य राष्ट्र के हित में नहीं भी हो सकते हैं। दूतावास के पास इतने रुपए हो गये थे, तो वह भारतीय लोगों से मनमाने काम करा सकता था। इसका इस्तेमाल जासूसी कराने में भी हो सकता था। प्रभावशाली लोगों को इससे 'खरीदा' भी जा सकता था। सरकार जब उपभोग घटाने के लिए खर्च सीमित करना चाहती, तो यह पैसा बाजार में उतर कर उसके लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता था क्योंकि सामान कम और पैसा अधिक होने से कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं।

इसलिए खाद्यान्न की कमी देश और उसके अधिकांश लोगों के लिए ढेर सारी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। महंगाई तो खैर आती ही है! आयात सिर्फ महंगा ही नहीं पड़ता, बल्कि इसमें ढेर सारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी चली जाती है जिसकी हरदम कमी ही रहती है। खाद्यान्न की महंगाई का अर्थ बाजार की हर चीज की कीमत का बढ़ना होता है। विदेशों पर आश्रित होना भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इससे सरकार पर बड़ी ताकतों का दबाव बढ़ जाता है। अगर हमारी विदेश नीति का कोई पहलू किसी बड़े देश के मनमुताबिक नहीं हो, तो वह भारत सरकार का कान उमेठकर उससे मनमुताबिक बदलाव करा सकता है।

खाद्यान्न के निर्यात का भारी खर्च भी कृषि और उद्योगों के विकास के लिए अपने आप एक गंभीर समस्या है। विदेशी मुद्रा की कमी हरदम रहती है। इसी में अनाज भी खरीदना होता है फिर रासायनिक खाद, मशीनरी और उद्योग के अन्य कच्चे मालों को खरीदने के लिए कम पैसा बचता है।

गरीबों की पिसाई: इस सबमें गरीब ही बुरी तरह पिसा जाता है। परिवार की आमदनी जितनी कम होती है, अनाज वगैरह खरीदने में उसका उतना ही बड़ा भाग खर्च होता है। अनाज की कीमत बढ़ने का अर्थ इन परिवारों पर अधिक बोझ बढ़ना होता है। शहरों में निम्न मध्यम वर्ग इस चक्की में पीसा जाता है। राशन में मिलने वाले अनाज की मात्रा कम कर दी जाती है और यह पूरे परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। इसलिए खुले बाजार से भी अनाज लेना होता है, जहां कीमतें काफी ऊंची होती हैं।

पर अन्न की कमी का असर और भी होता है। अधिकांश घरों में ऐसी स्थिति में अन्य चीजों को खरीदने के लिए कम पैसा बचता है। कपड़ा, जूते, खाने के तेल और यहां तक कि दवा की खरीद में भी कमी हो जाती है। लोग त्यौहारों पर कम खरीदारी करते हैं। कपड़े और जूता उद्योग तो त्यौहारों की बाट जोहते बैठे रहते हैं। पर अधिकांश ग्रामीण परिवार खाने की जरूरत ही पूरी करने के लिए अन्य चीजों की खरीद बंद कर देते हैं।

संक्षेप में कहें, तो औद्योगिक सामान बुनकरों, कुम्हारों जैसे लोगों द्वारा निर्मित सामान की मांग घट जाती है। नतीजतन उत्पादन घट जाता है और इससे रोजगार भी कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में पूरा औद्योगिक विकास ही धीमा पड़ जाता है। कृषि का विकास रुक जाता है और अकसर देश की सार्वभौमिकता भी खतरे में पड़ जाती है। लगता है कि देश इसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार के किसी फैसले से ऐसा नहीं लगता कि वह देश की खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को बनाये रखने के लिए जागरूक है। साथ ही अनाज की कमी की ओर तेजी से बढ़ते जाने से भी यह स्थिति बनती जा रही है।

—कुमारेश चक्रवर्ती

डोमिनीक लेपियरे

१९५२ में १८ वर्षीय फ्रांसीसी लेखक डोमिनीक लेपियरे अपनी सद्यः विवाहिता पत्नी डोमिनीक के साथ समूचे विश्व में अपना हनीमून मनाते हुए कलकत्ता पहुंचे, तो उन्हें सपने में भी यह भान नहीं था कि कुछ अरसे के भीतर भी भारत उनकी उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्रोत बन जायेगा और वह १९७६ में भारत की आजादी विषयक 'फ्रीडम ऐट मिडनाइट' जैसी पुस्तक लिखकर हंगामा मचा देंगे। इस पुस्तक की एक करोड़ से भी अधिक प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं तथा विश्व की अधिकांश भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। कई देशों के प्रकाशक उस पुस्तक की डुप्लीकेट प्रतियां छापकर मालामाल हो चुके हैं और उन पर उनके देश में चार सौ बीसी के मुकदमे चल रहे हैं।

वही डोमिनीक लेपियरे अब रिचर्ड एटनबरो की गांधी से भी बड़ी लागत की फिल्म का निर्माण करा रहे हैं, जिसकी आमदनी कलकत्ता में अनाथों, बेसहारों, अपंगों आदि के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए दे दी जायेगी। लगभग ३० करोड़ रुपए की लागत से बननेवाली यह फिल्म डोमनीक लेपियरेलैरी कोलिंस द्वारा कलकत्ता की झुग्गी-बस्ती की जिंदगी पर लिखित उनकी नवीनतम १९८७ में प्रकाशित बेस्ट सेलर उपन्यास 'सिटी आफ ज्वाय' पर आधारित होगी। 'सिटी आफ ज्वाय' की ७० लाख से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और विश्व की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है या हो रहा है।

डोमिनीक १९८१ में अपनी पत्नी के साथ दूसरी बार कलकत्ता आये थे। 'सिटी आफ ज्वाय' के लिए उन्होंने कलकत्ता की झुग्गी-बस्ती आनंद नगर चुनी, जहां वह अपनी पत्नी के साथ दो वर्षों तक झुग्गीवासियों की ही तरह रहे। 'सिटी आफ ज्वाय' छपने पर समूचे विश्व से लगभग एक लाख पत्र मिले। बहुतों ने अपने पत्र के साथ धन, आभूषण आदि उनके पास भेजे कि वह इन्हें अपने 'हीरोज' (आनंदनगर के बाशिंदों को वे हीरोज मानते हैं) को दे दें।

डोमिनीक अपनी पुस्तकों की रायल्टी का अधिकांश भाग आनंदनगर तथा कुष्ठ रोगियों एवं अपंगों की संस्था को दे देते हैं और अपना अधिकांश समय उनके बीच रहकर उनकी सेवा-सहायता में व्यतीत करते हैं।

अमिताभ बच्चन

शहंशाह (अमिताभ बच्चन) को आशा थी कि 'शहंशाह' रिलीज होते ही उसके गर्दिश के बादल छंट जायेंगे और 'मिस्टर क्लीन' वाला सिंहासन उसे वापस मिल जायेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पिछले साल अगस्त में 'शहंशाह' रिलीज होनी थी, मगर लगभग पांच महीने बाद भी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल अक्तूबर में जब बोफोर्स और फेयरफैक्स की हवा गर्म थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि अमिताभ इनसे निपटने के लिए अपने जिन 'शहंशाह' को डिब्बे से आजाद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिन था कि डिब्बे से बाहर आने को तैयार नहीं था। नवंबर में दलील दी गयी कि रिलायंस कप के शोर-शराबे में थियेटर कौन जायेगा? अगली तारीख दिसंबर में तय की गयी। इसी बीच शिवसेना वालों ने थियेटरों के सामने धरना देने की धमकी दे डाली। चुनांचे मामला एक बार फिर टल गया।

बहरहाल, उम्मीद थी कि आरोपों से छलनी अभिताभ नये साल का स्वागत 'शहंशाह' को रिलीज करवाकर करेंगे और खबर भी कुछ ऐसी ही आयी। घोषणा हुई कि १२ फरवरी को 'शहंशाह' आजाद होगा, लेकिन घोषणा के पंद्रह दिन बीतते-न-बीतते यह तारीख भी टल गयी।

'शहंशाह' के रिलीज न होने के कई कारण बताये जा रहे हैं, मगर दम दो ही में नजर आ रहा है। एक खबर यह है कि राजनीतिक दल कहीं उनकी फिल्म के खिलाफ विरोध अभियान शुरू करके फिर से कोई नया बावेला न खड़ा कर दें, जिससे कहीं लेने-के-देने न पड़ जायें। दूसरा कारण वितरकों में फिल्म के बारे में फैला भय बताया जा रहा है। वितरकों का कहना है कि यदि अमिताभ की छवि और बिगड़ी, तो फिल्म बाक्स आफिस पर दस साल तक टिक नहीं पायेगी और उन्हें घाटा होगा।

वैसे, कुछ लोगों का यह भी कयास है कि अमिताभ इलाहाबाद उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उनका खयाल है कि शहशाह की लोकप्रियता के जरिये वह फिर चुनाव जीत सकते हैं और एक बार फिर शहंशाह की माफिक सिर उठाकर संसद में दाखिल हो सकते हैं।

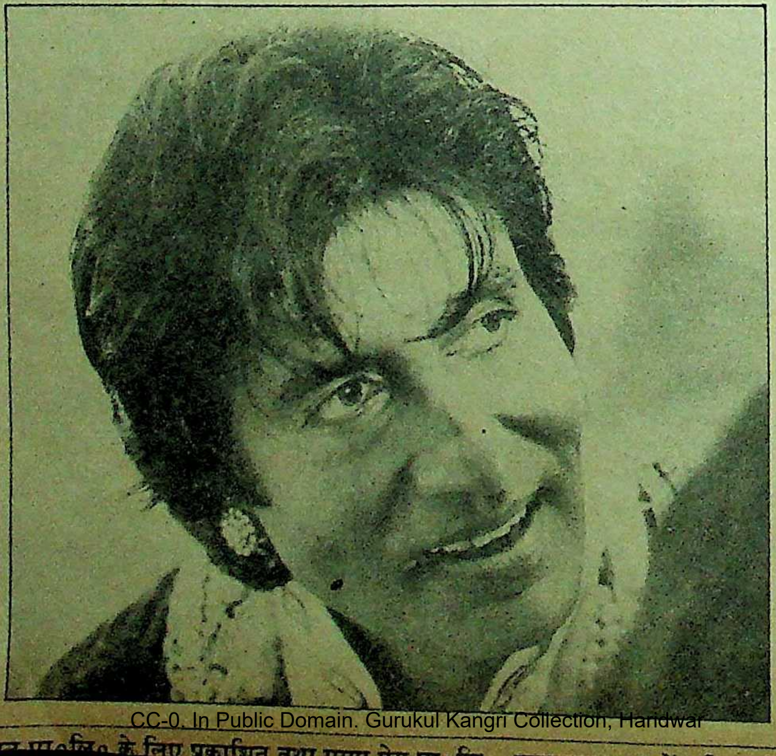

रिचर्ड हैडली

न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी रिचर्ड हैडली ने इयान बाथम के सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकार्ड की बराबरी करके सर्वश्रेष्ठ आल राउंडर का अपना दावा और पुख्ता कर लिया है। मेलबोर्न में आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में जब उन्होंने ए० डोडीमोड का विकेट लिया, तो उनका यह ३७३वा विकेट था। इस पारी में उन्होंने पांच विकेट लिये।

हैडली को न्यूजीलैंड की टीम की रीढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि हैडली के बिना न्यूजीलैंड कभी मैच नहीं जीत सकती और ज्यादातर ऐसा हुआ भी है। रिलायंस कप में न्यूजीलैंड के फिसड्डी रहने की एक वजह हैडली की अनुपस्थिति ही थी।

बाथम के रिंकार्ड की बराबरी करने पर हैडली ने ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की। उनका कहना था, "मेरा लक्ष्य तो ४०० विकेट लेने का है। अभी तो मंजिल का एक हिस्सा ही मैंने पार किया है।"

वैसे हैडली ने एक पारी में पांच से ज्यादा विकेट ३२ बार और एक टेस्ट में दस या उससे ज्यादा विकेट लेने का करिश्मा १० बार दोहराया है। —दिनेश दीनू

प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,

151728

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
DUPLICATE

दावणगेरे

फ़ैशन फ़ैब्रिक्स

नर्म-मुलायम बनावट वाले
प्रिया और प्रेमिका टेरीन * साड़ियां
—मनमोहक डिज़ाइनों में
हर एक की पसंद के अनुरूप
अनेकों खूबसूरत, लुभावने
रंगों में.

साथ ही उपलब्ध
- सूटिंग्स • शर्टिंग्स
- ड्रेस मटीरियल्स
- कैम्ब्रिक
- टू × टू रूबिया • टर्किश टॉवेल्स

दि दावणगेरे कॉटन मिल्स लिमिटेड
हनुमानथप्पा बिल्डिंग्स, चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.

शोरूम: कावेरी भवन, बंगलौर-५६० ००९
दाजीबन पेठ, हुबली-५८० ०२०, चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.

T/8788/D/HIN

* टेरीन काफ़ी का ट्रेडमार्क है

परिपूर्ण नारी की
एकमात्र परिभाषा : 'मनोरमा'

१९२४ से आज तक
मनोरमा का ध्येय रहा है
आपके जीवन को आपके लिए,
आपके परिवार के लिए और समाज के लिए
और अधिक सार्थक बनाना।

आपके जीवन के हर मोड़ पर
मनोरमा एक मित्र,
मार्गदर्शक और जानकार विशेषज्ञ के रूप में
आपकी समस्याएं और
उलझनें सुलझाती है,
शिक्षा, नौकरी एवं व्यवसाय के क्षेत्र की
नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देती है,
सौंदर्य, फ़ैशन तथा तहज़ीब पर
सलाह दे आपका व्यक्तित्व निखारती है,
व्यंजन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और गृहसज्जा आदि
की नई विधियों से आपका
परिचय कराती है,
पारिवारिक रिश्तों, बच्चों की
समस्याओं इत्यादि पर
सुझाव और मनोवैज्ञानिक लेखों
के माध्यम आपकी मुश्किलें आसान बनाती है
—यानी हर तरह से
आपको एक संपूर्ण नारी
बनने में सहायक की भूमिका निभाती है।

मनोरमा आपके मनोरंजन का
पूरा ध्यान रखती है। मनोरमा के
हर अंक में आपको मिलेंगी
जाने-माने साहित्यकारों द्वारा लिखी कहानियाँ
व कविताएं, व्यंग्य का कॉलम
'फ़ुरसतनामा', कार्टून कथाएं— 'चन्नी चाची'
और 'श्रीमती जी', चुटकुले और
ढेर सारे नियमित स्तंभ।

यदि आपने मनोरमा का नया अंक नहीं पढ़ा
तो आज ही खरीदिए
क्योंकि—मनोरमा में वह सब कुछ है जो आप
पढ़ना चाहती हैं।

महिलाओं की एकमात्र संपूर्ण पत्रिका

मनोरमा

कामयाब महिलाओं की
कामयाब पत्रिका

हर पन्द्रह दिन पर प्रकाशित • हर अंक एक विशेषांक

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक ४

२१ फरवरी, १९८८

माया

यह अंक

आवरण कथा

राजीव की इज्जत
इलाहाबाद लोकसभा सीट

३० सारे देश की आंखें अमिताभ बच्चन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई लोकसभायी सीट के उपचुनाव पर टिकी हैं। बोफोर्स के विवाद के बाद अमिताभ ने इस्तीफा दिया है और इलाहाबाद राजा का गृहनगर है। इसलिए यह माना जा रहा है कि यह चुनाव यह तय करेगा कि कौन कितने पानी में है। क्या अमिताभ बच्चन यहां से फिर खड़े होंगे? यदि वह चुनाव लड़ें तो परिणाम क्या होगा? 'माया' द्वारा किये गये जनमत संग्रह के साथ इस ऐतिहासिक उप चुनाव का बहुआयामी विश्लेषण:

विशेष रिपोर्ट

नये धारावाहिक 'तमस' में ऐसा क्या है, जिसके कारण वह दूरदर्शन के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद बन गया? १४

राजस्थान

हरिदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस परिवर्तन के बाद राजस्थान की राजनीति क्या मोड़ लेगी? ४७

महेन्द्र सिंह टिकैत

टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसानों ने मेरठ में जो शक्ति प्रदर्शित की है, उससे इंका किस संकट में फंस गयी है? ५७

प्रणब

काफी दिनों तक ना-नुकुर करने के बाद प्रणब फिर कांग्रेस में लौट आये हैं। उनकी वापसी किन शर्तों पर हुई? ७०

पंजाब

नये साल के पहले ही महीने में आतंकवादियों ने २०० से भी ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं। आतंकवाद में इस भयावह वृद्धि का कारण क्या है? २४

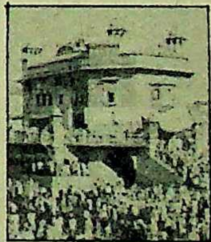

मध्य प्रदेश

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव राम रतन राम प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के लिए परेशानी का कारण क्यों बन गये हैं? ५१

दिल्ली दरबार: बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाये? ६
साक्षात्कार/अली सिद्दीकी: वी०पी० सिंह सोचते थे वह भारत के प्रधानमंत्री बन जायेंगे २०
विशेष: वित्तमंत्री को खुलापत्र २२
पंजाब: बादल और बलवंत सिंह से बातचीत २४
बिहार: कौन है सिंहासन का उत्तराधिकारी? ५३
बिहार: सोने की खोज ५५
उत्तर प्रदेश: वीर बहादुर हटाओ अभियान ६२
उत्तर प्रदेश: वीर बहादुर बनाम ब्रह्मदत्त ६८
देश: गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन ७२
खेल: नरेंद्र हीरवानी का करिश्मा ७६
खेल: हाकी से राजनीति का रंग कब उतरेगा? ८०
घटनाक्रम: तमिलनाडु में राजनीतिक संकट ८४
विवाद: एयर टैक्सियां: दलाली का नया स्रोत ८६
फिल्म: डिंपल-राजेश खन्ना का मिलन? ९७

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपालां अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया
जयललिता बनाम जानकी

इस पार या उस पार

'माया' का जनवरी (द्वितीय पक्ष) अक हाथ में आते ही इसके पन्नों को पलटने लगा। जब पृष्ठ ३० आंखों के सामने आया, तो पहले इसे पूर्णरूपेण पढ़ा। 'माया' ने हमारे प्रधानमंत्री को 'उस पार' होने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। यदि राजीव उन्हें जरा ध्यान दें, तो वे अपनी कठिनाइयों और विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में 'माया' ने सचमुच देश के हित में काम किया है। —**राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अफाल, बर्दवान प० बंगाल**

विपक्ष का नया पक्ष

'माया' (३१ जनवरी) में प्रकाशित रिपोर्ट 'विपक्ष का एक नया पक्ष' पढ़ा। १९७७ में जनता पार्टी के रूप में बिखरे विपक्षी नेताओं का गठबंधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का आश्चर्य है, लेकिन शीघ्र ही व्यक्तिवाद की क्षुद्र मानसिकता दृष्टिगोचर होने लगी और जनता पार्टी का बिखराव होने लगा। तब से अब तक विपक्षी गठबंधनों के अनेक असफल प्रयास हो चुके हैं। हाल ही में वी०पी० सिंह के नवगठित जनमोर्चा के साथ, जनता, लोकदल-अ, और कांग्रेस-स के गठबंधन से बने राष्ट्रीय मोर्चा की सफलता भी संदिग्ध है, क्योंकि लगातार नसीहत के बाद भी भारतीय नेता स्वनेतृत्व की भावना से छुटकारा नहीं पा सके हैं। यदि वी०पी० सिंह के नेतृत्व में दलों और नीतियों के गठबंधन के साथ-साथ नेताओं का भी विश्वसनीय गठबंधन किया जा सके, तो निश्चय ही 'राष्ट्रीय मोर्चा' सशक्त विपक्ष होगा। —**संजय चतुर्वेदी, पातरापरी घाट, भोपाल, म०प्र०**

विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित 'विपक्ष का एक नया पक्ष' रिपोर्ट से मैं काफी हद तक सहमत हूं। पिछले कई वर्षों से विपक्ष लगातार एक जुट होने की बात करता हैं और सही मायने में अभी उसका यही एकमात्र लक्ष्य है। उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पर है कि किस तरह हम एक जुट हो वर्तमान सत्ता में परिवर्तन कर सत्ता हासिल कर सकें। सत्ता प्राप्ति ही उसका एकमात्र कार्यक्रम है। पर हास्यास्पद और विडंबना ही यह है कि वे जितना ही मिलने की बात करते हैं, उतना ही वे एक दूसरे से अलग होकर नई पार्टियों को जन्म दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा जनमत पाने के लिए आवश्यक है कि निःस्वार्थ भाव के साथ ये अपने को एक जुट कर एक ठोस कार्यक्रम के साथ जनता के सामने आयें। अतः विश्वास पाने के लिए ठोस कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता है। इसके अभाव में इनका प्रयास अलगाव या फूट को ही बढ़ावा देगा। —**अरुण कुमार, हास्टल-२, क्रमरा नं० ११ अप, आर०बी०एस० कालेज आगरा, आगरा परिसर—आगरा, उत्तर प्रदेश**

'विपक्ष का नया पक्ष' (माया, ३१ जनवरी '८८) पढ़कर मन में यह खयाल आया कि असल में विरोधी दल के एकता-प्रयास का पूरा 'एप्रोच' ही गलत है और ऐसा इस कारण है कि ये लोग राजनीतिक तथ्य का वस्तुगत विश्लेषण या तो करना नहीं जानते या करना नहीं चाहते। विरोधी दल की सारी राजनीति इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि कैसे हम नेहरू राजवंश को विदा दें और फिर भी देश में लोकतंत्र और विचार-स्वातंत्र्य न केवल कायम रहे, वरन् और मजबूत हो। दूसरे शब्दों में सर्वहाराओं या आम आदमी की तानाशाही न केवल बनी रहे, वरन् और मजबूत हो। —**आशीश कुमार चौधरी, बलभद्रपुर, लहेरिया, दरभंगा, बिहार**

काम कम तमाशा ज्यादा

३१ जनवरी, १९८८ के अंक में प्रकाशित 'काम कम तमाशा ज्यादा' पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि देश को २१वीं सदी में ले जाने वाले (ढकेलने वाले) कंप्यूटर शिक्षा का प्रयास करनेवाले, सफारी पसंद प्रधानमंत्री को भारत एवं भारत के गरीब मतदाताओं की कितनी चिंता है जिन्होंने उन्हें १९८४ के लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जिताया। जो प्रधानमंत्री भारत की जनता के पैसों से बनाये गये हेलीपेड का प्रयोग न करके आयातित कार से सफर करना पसंद करता है, आयातित पलंग पर सोना चाहता है, उसके नेतृत्व में देश कभी तरक्की नही कर सकता। मात्र मंत्रिमंडलीय बैठक के लिये सरिस्का का टाइगर डेन बुक कर लेना जिससे जनता का लाखों रुपया आसानी से फूंका जा सके, यह तमाशा नहीं तो और क्या है? —**प्रभुदयाल, असाटी और अशोक सिंह बैस, पो०—लामता, जि०—बालाघाट, मध्य प्रदेश**

दो महिलाओं का सत्ता संघर्ष

'माया' का फरवरी प्रथम अंक पढ़ा। आवरण कथा 'दो महिलाओं का सत्ता संघर्ष' ठीक लगी, लेकिन इसका विश्लेषण और बेहतर ढंग से हो सकता था। मुद्दों और परिस्थितियों पर यदि और गौर किया जाता, तो रपट में जान आ सकती थी। कितनी विचित्र बात है कि एक राष्ट्रीय पत्रिका की आवरण कथा केवल घटनापरक हो।

एमजीआर की मृत्यु के बाद तमिलनाडु में सत्ता की जो लड़ाई शुरू हुई, उसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दीं। मुख्यमंत्री की गद्दी मानो किसी की जायदाद हो गयी कि पति के मरने पर पत्नी को मिलनी चाहिए। राजनीति के मामले में शून्य जानकी मुख्यमंत्री पद पर बैठने में कामयाब हो गयीं। दूसरी तरफ एमजीआर की मित्र जयललिता भी इस राजनीतिक विरासत को पाने के लिए मैदान में उतर आयीं।

वैसे देखा जाये, तो मौजूदा हालातों के लिए एमजीआर भी कम दोषी नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि अपने दस वर्ष के शासन काल में उन्होंने तमिलनाडु को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, मगर अपनी पार्टी में उन्होंने निरंकुशता से काम लिया। अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि माना। अन्नाद्रमुक में लोकतंत्र उन्होंने पनपने ही नहीं दिया। लिहाजा, उनकी मृत्यु के बाद नेताओं की दूसरी पंक्ति तैयार ही नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में अवसरवादी राजनीति को प्रोत्साहन तो मिलना ही था। —**संजय खरे, मिनिस्टर रोड, बुढ़ार, मध्य प्रदेश**

शर्मनाक उपलब्धि

३१ जनवरी '८८ के 'माया' का अवलोकन करने पर लगा कि राजस्थान सरकार ने अपने २ वर्षों से कुछ ज्यादा के कार्यकाल में उपलब्धियों के रूप में हत्या, भ्रष्टाचार, दिवराला सती काण्ड और (अब) नरबलि ही प्राप्त की है। जो निःसंदेह एक शर्मनाक उपलब्धि है और लगता है इसी का परिणाम हमारे मुख्यमंत्री का इस्तीफा रहा है। —**कैलाश निर्मोही, ग्रीन हाउस, रींगस**

महान व्यक्तित्व

आपने ३१ जनवरी '८८ की 'माया' के 'एक युग का अंत' लेख में एमजीआर के जीवन चरित्र के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। एमजीआरजी का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। —**सोहन लाल शुक्ल, ग्राम-लखनीपुर फरेंदा, पो०-तहसील-बलरामपुर, गोण्डा**

अब नरबलि

'माया' (३१ जनवरी) में माता-पिता द्वारा पुत्रबलि के बारे में पढ़ा। नरबलि जैसी नृशंस घटनाएं आज भी होती हैं, यह सोचकर काफी दुःख पहुंचा। अंधविश्वासों से युक्त पिछड़ी मानसिक अवस्थावालों की उपस्थिति आज भी हमारे समाज में है। सती जैसी घटनाओं से भी ज्यादा घृणित ये कलंक (नरबलि) आज भी छिपकर होते ही रहते हैं। सती प्रथा में 'देवी जैसा पद' पाने की लालसा भी एक उत्प्रेरक का काम करती है, पर नरबलि के लिए प्रयुक्त उन अभागे बेचारों की स्थिति का तो अंदाजा लगाइये। इस तरह की हत्याएं करनेवालों के लिए तो मृत्युदंड भी बहुत कम है। —**जयकांत, वैशाली**

महंगाई की मार

'माया' के ३१ जनवरी के अंक में 'सरकार पर भी पड़ेगी महंगाई की मार' शीर्षक से प्रकाशित आर्थिक आलेख सरसरी तौर पर पढ़ा। भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़-सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों में समन्वय,

तर्कसंगत कर-संरचना, उत्पादन-वृद्धि के लिए प्रबंधन एवं मजदूर के लिए स्वस्थ-वातावरण तथा निर्जीव नीति-निर्धारक संस्थाओं में भ्रष्टाचार एवं कैंसर की तरह बढ़ती राजनीतिकरण से मुक्ति की दिशा में प्रयास करते हुए ईमानदार दृष्टियुक्त नयी आर्थिक संस्कृति विकसित हो।—**वरुण कुमार मिश्र, ब्रंजारी रोड, गोपालगंज**

सराहनीय

मुझे बड़े हर्ष के साथ यह लिखना पड़ रहा है कि आपके ३१ जनवरी के अंक में 'दिल्ली दरबार' बहुत ही रोचक एवं मनोरंजनपूर्ण था। आप 'लोकरुचि समाचार' जैसा कोई स्तभ चलायें, तो आपकी 'माया' और भी रोचक होगी।—**रामजी द्विवेदी, गांव-शमसपुर, पों० चरवा, जनपद-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश**

क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी गयी?

'क्या मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी?' शीर्षक लेख हिंदू समाज के लिए काफी दुखद है। श्री सूशील श्रीवास्तव ने दूसरे वर्ग के लोगों से पुरस्कार लेकर इस तरह की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। उनके लेख को आपको नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि एक वर्ग के लोग पढ़ने के बाद काफी दुखी हुए हैं और दूसरा वर्ग उत्साहित हुआ है।—**वीरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम-पो० भीरसंड, वाया-रुन्नी सैदपुर, जिला—सीतामढ़ी, बिहार**

'माया' के १५ जनवरी '८८ के अंक में सर्वाधिक दिलचस्प थी आवरण कथा, जिसमें असलियत खोलकर रखी गयी है जिससे 'माया' की निर्भीकता पर विश्वास बढ़ा। सचमुच बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद को पढ़कर लगा कि जिसकी किसी को नहीं है खबर, 'माया' रखती है उसकी खबर। मेरे विचार से अब भगवान भरोसे चल रहा है यह देश। आवरण कथा के द्वारा हिंदू-मुस्लिम मानस को गहराई से जानने एवं समझने की कोशिश की गयी है। धन्यवाद लेखक को जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है।—**शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, स्टेशन रोड, पो० सक्ती, मध्य प्रदेश**

'माया' का १५ जनवरी '८८ का अंक पढ़ा, अंक की आवरण कथा 'क्या मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी गयी?' पढ़कर मन को पीड़ा पहुंची, क्योंकि इस प्रकार के नये ऐतिहासिक तथ्य जानकर हम क्या करेंगे? उस मामले को मिल-बांटकर, दोनों मज़हबों में भाई जैसा वातावरण तैयार कर, उक्त विवाद को हमेशा के लिये समाप्त कर दें ताकि आने वाली पीढ़ी इस दुखमयी समस्या में न उलझे।—**विजय कुमार पहूजा, १३३/१, बी०के० सिंधी कालोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश**

एक अभूतपूर्व शादी

'माया' के जनवरी प्रथम अंक में 'एक अभूतपूर्व शादी' नामक लेख पढ़ा। इसे पढ़कर कौन कह सकता है कि भारत एक गरीब देश है। कोई यह कैसे कह सकता है कि भारत वही देश है जहां किसी-किसी घर में चूल्हा तक नहीं जलता। ३० करोड़ तो दूर ३०० रुपयों के लिए कितने लोगों को कैसे-कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर अगर सिंधिया साहब बाहरी दिखावा न कर गरीबों के लिए कुछ कर देते जो जीतोड़ परिश्रम करके दो रोटियां खाकर संतोष करते हैं, जो अधिक ठंड में अलाव जलाकर तापते हैं, तो उनके लिए शायद वह ज्यादा बड़प्पन का काम होता।—**संजय कुमार सिंह, बी०एस० के० कालेज, धनबाद**

'माया' के १५ जनवरी '८८ के अंक में प्रकाशित 'फोटोफीचर' देखकर तथा 'एक अभूतपूर्व शादी' शीर्षक रिपोर्ट पढ़कर उद्वेग एवं आक्रोश से भर गया। उद्वेग इस बात से हुआ कि आजादी की प्राप्ति के चालीस वर्षों के बाद भी हमारे देश की जनता मानसिक रूप से गुलाम ही बनी हुई है तथा अभी भी ब्रिटिश काल या गुलामी के दिनों की सड़ी-गली व्यवस्थाओं में आस्था रखती है। आज भी अधिकांश देशवासी विशेषतया भोले-भाले-ग्रामीण कुछ राजा-प्रजा या गुलामी की मानसिकता और कुछ अपनी कायरता तथा गुलामी के जमाने के जन शोषकों के आतंक या वाह्यांडबर के प्रभाव के शिकार हैं। इसी प्रभाव का परिणाम है कि इन तथाकथित राजाओं का जब कोई उत्सव होता है, तो वे न केवल धन-श्रम सभी दृष्टि से उनको सहयोग देते हैं, बल्कि अपने सहयोग को भी हीन-दृष्टि से देखते हैं।—**वैद्यनाथ पाण्डेय, द्वारा श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, राजकीय औषधालय बिहिया, पो० बिहिया, जिला—भोजपुर**

खयालात

देवीलाल

जानकी रामचंद्रन

दीप्ति नवल

जो मेढक सांप के करीब होते हैं, उनको तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है।—**एम करुणानिधि, (एआईडीएमके द्वारा कांग्रेस की मदद पर टिप्पणी)**

प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के संबंध 'बाजारू'-से बन गये हैं।—**'दिनमान' के अतिथि संपादक हेमवती नंदन बहुगुणा**

मैं हमेशा मजलूमों का साथी था, हूं और रहूंगा। उस मजलूम का मज़हब कोई भी हो, उसके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा।—**सैयद अब्दुल्ला बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद**

चार वर्षों से मुझे कांग्रेस से निकालने अथवा छोड़कर चले जाने की कोशिश की जा रही है।—**डा० जगन्नाथ मिश्र**

राजीव गांधी पार्टी और सरकार को कंपनी के निरंकुश मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से चला रहे हैं।—**देवीलाल 'जनसत्ता' में**

संगठन और सरकार का रिश्ता अब चोली-दामन का होगा...अब राजस्थान नौकरशाहों के बूते पर नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी से चलेगा।—**मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शिवचरण माथुर का वक्तव्य, 'चौथी दुनिया' में**

कांग्रेस एक संगठनहीन पार्टी है।—**ए०बी०ए० गनी खान चौधरी, 'रविवार' में**

मैं एक कवि हूं और मूडी हूं। जब मेरा मूड बदलता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं।—**सुवास घीसिंग, 'टेलीग्राफ' में**

'तमस' सीरियल ने मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों को महिमा-मंडित किया है जबकि असलियत यह है कि दोनों ही भारत के बंटवारे के जिम्मेदार हैं।—**कृष्णलाल शर्मा, महामंत्री भाजपा 'हिंदुस्तान टाइम्स' में**

मैं अमिताभजी के खिलाफ नहीं हूं। अगर राजीव गांधी उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, तो मैं उनका पूरा समर्थन करूंगा।—**पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी (इलाहाबाद से), 'धर्मयुग' में**

मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों ने मेरे स्वर्गवासी पति को 'भारत रत्न' से अलंकृत किया, वे ही लोग मेरी सरकार को गिराने का प्रयत्न करेंगे।—**जानकी रामचंद्रन, 'इंडियन एक्सप्रेस' में**

विपक्षी दलों की एकता एक मृगतृष्णा है।—**रामकृष्ण हेगड़े, 'इंडिया टुडे' में**

मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यदि मेरा नाम 'पद्मभूषण' के लिए संस्तुत करना हो, तो करें वरना मैं इससे कम कोई पुरस्कार नहीं लूंगा।—**हेमंत मुखर्जी**

मैं जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूं, गाड़ी-बंगले के लिए नहीं, ढेर सारी किताबें खरीदने के लिए ताकि दूसरे देशों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकूं।—**दीप्ति नवल, 'माधुरी' में**

बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाये ?

जब 'हरहर महादेव' की गरजना के साथ 'सती मां' को याद करके हरिदेव जोशी ने सिर पर सवार बूटा सिंह को यह कह कर धोबीपाट मारा कि 'नहीं देता, तू क्या कर लेगा' तो बूटा सिंह को दिन में तारे नजर आने लगे। वह उठे। अपनी शेरवानी को बिना झाड़े, लाल-पीले-नीले होते हुए अर्जुन सिंह के टेलीफोन पर सवार होकर दिल्ली दरबार से मुखातिब हो गये—"सर, जोशी कब्जे में नहीं आ रहा है। कहता है कि आजादी की लड़ाई में बम ने उसके एक ही हाथ को उड़ाया है। दूसरा हाथ अभी भी सही सलामत है। दूसरे हाथ से पूरा दिल्ली दरबार उड़ा दूंगा।" दिल्ली दरबार ने 'बम' का नाम सुनते ही टेलीफोन पर बूटा सिंह को कोई हिदायत देने के पहले 'रेड एलर्ट' का साइरन बजवा दिया। बूटा सिंह सर सर...टेलीफोन पर करते रहे। लेकिन दिल्ली दरबार की ओर से मात्र साइरन के बजने की आवाज आती रही। बूंटा सिंह ने टेलीफोन का चोंगा वैसे का वैसा छोड़, तांडव कर रहे हरिदेव जोशी के चरणों को पकड़ लिया—"अरे परशुराम की औलाद, मुख्यमंत्री की कुरसी से इस्तीफा दे दो। मेरी नहीं, दिल्ली दरबार की इज्जत पर बन आयी है। उसने पूरे दरबार में 'रेड एलर्ट' का साइरन बजवा दिया है। मुल्क में इमरजेंसी लगने का खतरा मंडराने लगा है।" हरिदेव जोशी ने काले नाग की तरह फुंकार मारते हुए कहा—"इमरजेंसी लगे या मार्शल-ला। सती भक्तों का तू और तेरा दिल्ली दरबार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।" बूटा सिंह सांस भर कर फिर से गिड़गिड़ायें कि उसके पहले शेरवानी की एक जेब से राजस्थानी विधायक दुलेराम ने अपनी मुंड़िया निकाल कर बूटा सिंह के कान में फुसफुसाया—"सरदारजी, जोशी का इस्तीफा-विस्तीफा छोड़ो, वह दिल्ली दरबार का सिरदर्द है। तुम तो मेरी और मांगी लाल आर्य को मंत्री-कुरसी पर बिठाने का इससे सौदा कर लो।" बूटा सिंह ने दुलेराम की चंदिया पर कसकर टीप जमाई, तो वह फिर से जेब में दुबक गये—"दुलेराम, यहां मेरी जान पर बन आयी है और तुझे मिनिस्ट्री की कुरसी की लगी हुई है। चुपचाप जेब में बैठा रह।" बूटा सिंह ने हरिदेव जोशी की फिर से चिरौरी शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले ही लुंगी लपेटे और मद्रासी पान चबाते हुए मूपनार आ धमके—"बूटा, तुम पीछे हटो। मैं जोशीजी से बात करूंगा। मूपनार ने हरिदेव जोशी को पुचकारते हुए जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा, तो जोशी ने तुरंत पीछे हटकर एक दुलत्ती जड़ी। मूपनार औंधे मुंह बूटा सिंह के पैरों में जा गिरे—"अरे मद्रासी तूने मुझे क्या जानकी या जयललिता समझ रखा है कि तेरे पुचकारने में आ जाऊं।" बूटा सिंह जब तक मूपनार को सहारा देकर उठाते, तब तक जोशी छुट्टे सांड की तरह अगल-बगल खड़े लोगों को सींग मारते हुए यह कह कर बाहर निकल गये "दिल्ली दरबार से कह देना कि हरिदेव जोशी की आंख-में-आंख मिलाकर इस्तीफा मांगे, तो मैं सोचूंगा। दरबारियों के कहने पर इस्तीफा देने के दिन अब लद गये।"

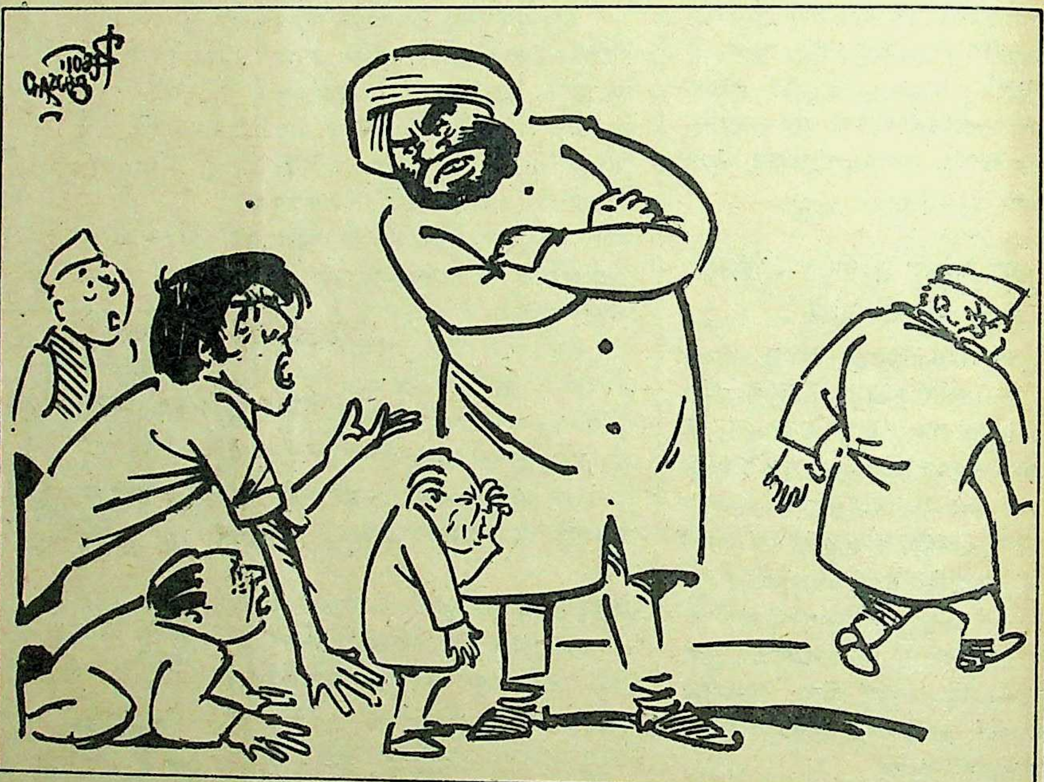

हरिदेव जोशी के जाते ही चूहों के बिलों से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। लम्बू यानी अमिताभ बच्चन ने बिल से अपनी गरदन निकाल कर इशारे से पूछा—"बूटा सिंह जी, क्या वह सती-भक्त चला गया?" बूटा सिंह ने मरी-सी गरदन हिलाकर 'हां' कही, तो धीरे से शिवचरण माथुर ने अपनी मुंड़िया निकाली। काले लबादे और हाथ में जादू की छड़ी लिये अशोक गहलौत निकले, तो उनकी गरदन बूटा सिंह ने पकड़ ली—"अबे, गोगिया पाशा की औलाद तू तो अपने आपको बहुत बड़ा जादूगर कहता फिरता था। कहता था कि मेरी जादू की छड़ी घूमेगी, तो हरिदेव जोशी फौरन इस्तीफा लिखने लगेगा। अब तेरा वह कलकतिया जादू कहां गया।" गहलौत ने अपनी गरदन को बूटा सिंह से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा—"बूटा भाई, मेरा जादू आजादी के बाद की पैदावार पर तो सिर पर चढ़कर बोलता है लेकिन आजादी के पहले की पैदावार पर कारगर नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शरण ली, इस हरिदेव जोशी को हटाने के लिए। अब तो तुम्हीं इस से निपटने का कोई उपाय करो।" बूटा सिंह ने अशोक गहलौत की गरदन छोड दी और सोचने के लिए अपनी खिजाबी दाढी खुजलाने लगे। दाढी खुजलाते-खुजलाते बूटा सिंह 'वाहे गुरु' को याद करके बुदबुदाने लगे—"घर (पंजाब) छोड कर घाट (जालौर-राजस्थान) गया। अब जब दिल्ली दरबार को पता चलेगा कि बूटा सिंह न घर का है और न घाट का, तो वह दाना-पानी लेकर मुझ पर चढ़ बैठेंगे। जो अपने रिश्तेदारों (अरुण नेहरू) और दून सखाओं (अरुण सिंह) के न हुए, वह मेरे क्या होंगे? यह अमिताभ तो कायस्थकुल की पुश्तैनी मधुशाला को बचाने के चक्कर में है। हे बूटा, लगता है तेरा उखड़ा-खूंटा! वाहे गुरु, कुछ कर। घर का नहीं, तो घाट का ही रख...।" बूटा सिंह दहाड़ मारने ही वाले थे कि पीछे से जगन्नाथ पहाड़िया ने आकर उनको अपने कंधे पर पड़ा तौलिया आंसू पोंछने के लिए थमाते हुए कहा, "भाई साहब, हम हरिजन शताब्दियों से इन अभिजात जातियों से प्रताड़ित रहे हैं। आगे भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप एक पंडत (हरिदेव जोशी) से लोहा ले रहे हैं। इस समुद्र मंथन का अमृत तो वह कायस्थकुल शिरोमणि शिवचरण माथुर ही झपट लेगा। हम

लोगों को तो विष का ही प्याला पीने को मिलेगा। कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि इस बार अमृत का प्याला मुझ जैसे हरिजन शिरोमणि के हाथ लग जाये।" बूटा सिह ने जगन्नाथ पहाड़िया के कंधे पर अपना सिर रख दिया—"पहाड़िया तू ठीक कहता है। लेकिन अगर हम लोगों ने अमृत पी भी लिया, तो क्या होगा। ये लोग उसे हम लोगों के पेट से बाहर निकलवा लेंगे। एक बार तूने अमृत का कटोरा (मुख्यमंत्री पद) पी लिया था। उसके बाद क्या हश्र हुआ। तेरे पेट की आंतें तक उस अमृत को वापस पाने के लिए निकाल ली गयीं। क्यों ऐसा भयानक सपना देखने की कोशिश कर रहा है। बचे-खुचे से ही काम चला। अगर माथुर मुख्यमंत्री हो जायेगा, तो तुझे सत्ता का टुकड़ा (मंत्रिपद) मिल ही जायेगा।" पहाडिया ने मायूसी में डूबते हुए बूटा सिह का मुंह-पुछा तौलिया वापस लेकर दूसरे कंधे पर डाल लिया और धीरे से उनका सिर अपने कंधे से हटाकर हवा में लटका दिया—"भाई साहब कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था।" बूटा सिह ने बात को बीच में ही काट दिया—"अरे पहले वह सती-भक्त इस्तीफा तो दे। वह तो अभी-अभी यह कह कर गया है कि दिल्ली दरबार उसकी आंख में आंख मिलाकर इस्तीफा मांगें, फिर मैं सोचूंगा।" पहाड़िया ने लपक कर बूटा सिंह की तरलित नाक को अपने कंधे पर पड़े तौलिये से पोंछा—"वह हरिदेव जोशी इस्तीफा देगा। अगर देगा नही, तो जायेगा कहां? राजस्थान की सारी कायस्थ नौकरशाही को शिवचरण माथुर ने एक लम्बे अरसे से जोशी के खिलाफ भड़का रखा है। उसकी जड़ों को कायस्थ ब्यूरोक्रेसी ने खोखली कर दिया है। बस उसे जहां एक धक्का लगा, वह चरमरा कर गिर पडेगा। आप जोशी के इस्तीफे को लेकर नाहक परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, आप एन०आर०आर० (नान रेजीडेन्ट राजस्थानी) हैं, इसीलिए खत का मजमून नहीं भांप पा रहे हैं। जोशी का बाप भी इस्तीफा देगा।" बूटा सिंह की बत्तीसी यह सुनकर खिलखिला उठी कि, 'जोशी का बाप भी इस्तीफा देगा।' उन्होंने आगे बढ़कर तौलिये की जगह पहाड़िया के कुरते से अपनी नाक पोंछ ली—"जगन्नाथजी तेरे बोल से मेरी रगों में अकाली खून एक मुद्दतों के बाद फिर से दौड़ने लगा।" बूटा सिंह पंचम में चीख पड़े—"बोले सो निहाल...।" पीछे से अशोक गहलौत ने अपने तिलस्मी शीशे पर जादू की छड़ी घुमाते हुए जवाब दिया—"सरदारजी शस्त्रीगाल। पकड़ लिया, पापड़ वाले को। यह देखो, इस तिलस्मी शीशे में देखो। वह रहा हरिदेव जोशी—जो अप्पू घर में सैर कर रहा है। दिल्ली दरबार अब जोशी की आंख-में-आंख डालकर कह सकेंगे कि इस्तीफा दो। तुम अप्पू घर में देखे गये हो, तुम दरबार-द्रोही हो। फौरन मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफा दो। बूटा सिंह ने गौर से तिलस्मी शीशे पर अपनी नजर जमायी, तो गहलौत ने जादू की छड़ी को घुमाकर जोशी को 'क्लोजअप' में लाकर खड़ा कर दिया। सोचने की मुद्रा बनाकर बूटा सिंह ने अपनी खिजाबी दाढ़ी खुजलाना शुरू किया—"अगर हरिदेव जोशी अप्पू घर में गया, तो इससे दिल्ली दरबार में उससे आंख मिलाने की ताकत कहां से आ जायेगी?" गहलौत ने उचक कर बूटा सिह के सिर पर जादू की छड़ी घुमायी—"अरे बूटा सिह तुम रहोगे 'वही के वही', चाहे मुल्क के पुलिसिया मंत्री कितने ही दिन क्यों न बने रहो। अरे हम लोग हरिदेव जोशी के इस अप्पू घर में जाने को 'इंटरप्रेट' कर लेंगे कि वह अरुण नेहरू के घर गया था। जैसे ही हम लोगों ने कहा कि हरिदेव जोशी इस्तीफे की बात सुनते ही, तुरन्त अरुण नेहरू के घर में देखा गया, तो दिल्ली दरबार गुस्से से लाल हो जायेंगे। उसी समय उनके सामने जोशी को हाजिर कर दो, वह फौरन से पेश्तर उससे इस्तीफा लिखवा लेंगे।" खुशी से बूटा सिंह की आंखें बाहर निकलने लगीं।

वह बोले, "चलो भाइयों, दिल्ली दरबार की ओर कूच करो।" सारे लोग बोले सो निहाल की उद्घोषणा के साथ दिल्ली दरबार की तरफ रवाना हो गये।

मणिशंकर ने घोषणा की, "दिल्ली दरबार अब वीर बहादुर सिंह का कत्थक नृत्य देखेंगे।" टिकैत की मेरठ की ओर से बढ़ रही सेना के भय से ध्यान हटाने के लिए वीर बहादुर सिंह लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का मेकअप करके महाराज बिन्दादीन की परन पर थिरकते हुए सामने आ गये। इसी बीच सैम पित्रोदा की टेक्नोलाजी ने काम शुरू कर दिया और दिल्ली दरबार नीले से लाल होने लगे।

लम्बू का इशारा पा कर शिवचरण माथुर 'लाल बाबा' के तंत्र-मंत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए फूट लिये। फूटने के पहले माथुर काफी 'नर्वस' थे। लम्बू (अमिताभ बच्चन) ने ढाड़स बंधाया—"अरे कायस्थकुल भूषण, जब मैं और बंटी (अजिताभ) दिल्ली दरबार के साथ लक्षद्वीप में छुट्टियां मना रहे थे, तो मैंने तुमको मुख्यमंत्री बनाने की बात उनके कंप्यूटर में फिट कर दी थी। तुम बिलकुल घबराओ नहीं। सब कुछ ठीक हो जायेगा। लाल बाबा की इस रट को कुछ दे ले के बंद करो कि माथुर अगर मुख्यमंत्री हो गया, तो ज्यादा दिन नहीं टिक पायेगा। नटवर सिंह दिल्ली दरबार के कंप्यूटर में यह 'फीड' कर रहा है कि लाल बाबा भी कह रहे हैं कि अगर मानसिंह की हत्या के आरोपी माथुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वह अपने पद पर ज्यादा दिन टिक नहीं पायेगा। याद रखना नटवर सिंह जाट है और जाट की काट आसान नहीं। मैं इस भीड़ के पहुंचने के पहले दिल्ली दरबार पहुंच कर उन्हें फिट करता हूं, तुम लाल बाबा को किसी तरह फिट करो कि माथुर लम्बे अरसे तक मुख्यमंत्री की कुरसी पर चिपका रहेगा।"

हरिदेव जोशी के 'अप्पू घर' जाने की बात सुनकर दिल्ली दरबार पहले पीले पड़े, फिर नीले हो गये।

नीले पड़े दिल्ली दरबार को अपने ओरिजनल कलर में लाने के लिए मणिशंकर अय्यर ने उपक्रम शुरू कर दिये। मणिशंकर ने घोषणा की, "दिल्ली दरबार अब वीर बहादुर सिंह का कत्थक नृत्य देखेंगे।" टिकैत की मेरठ की ओर से बढ़ रही सेना के भय से ध्यान हटाने के लिए वीर बहादुर सिंह लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का मेकअप करके महाराज बिन्दादीन की परन पर थिरकते हुए सामने आ गये। इसी बीच सैम पित्रोदा की टेक्नोलाजी ने काम शुरू कर दिया और दिल्ली दरबार नीले से लाल होने लगे। वह गरजे—"वीर बहादुर बंद कर यह कत्थक नाच। मुझे देख नहीं रहा है कि मैं गुस्से से लाल हो रहा हूं।" वीर बहादुर ने अपने पैरों के घुंघरू तुरंत उतार दिये और दुम दबाकर भागे। भागते ही दिल्ली दरबार के सामने हरिदेव जोशी को रस्सी में बांध कर हाजिर कर दिया गया।

दिल्ली दरबार 'लाल' होकर गरजे—"बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाये। मार दिया जाये, या छोड़ दिया जाये।" असहाय नजरों से हरिदेव जोशी ने दरबारियो की तरफ निहारा। जिस-जिस से जोशी ने निगाह मिलाने की कोशिश की, उस-उस ने अपनी निगाहें चुरा लीं। थोड़ी देर के लिए पी०वी० नरसिम्हाराव ने जोशी से आंख मिलाने की कोशिश की कि 'इस गरीब ब्राह्मण की हत्या क्यों की जा रही है!' लेकिन वह ज्यादा देर तक जोशी से आंख नहीं मिला पाये। उधर दिल्ली दरबार ने कहा, "इसी पल इस्तीफा देकर मेरी आग उगलती लाल आंखों से दूर हो जा।" हरिदेव जोशी ने अपनी रस्सी को कुछ ढीला करके दिल्ली दरबार से भाग जाने के लिए पैंतरेबाजी की, तो दिल्ली दरबार ने कसकर दहाड़ा—"भागने ना पाये। इसको पकड़ कर इस्तीफा लिखवा लो।" दिल्ली दरबार की दहाड़ सुनकर दरबारी हरिदेव जोशी पर टूट पड़े और मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफे पर उनका अंगूठा लगवा लिया।" दिल्ली दरबार गर्व से फूल उठे मानो खूंख्वार शेर को मार लिया हो।

—दरबारी लाल

अमिताभ की हिट लिस्ट

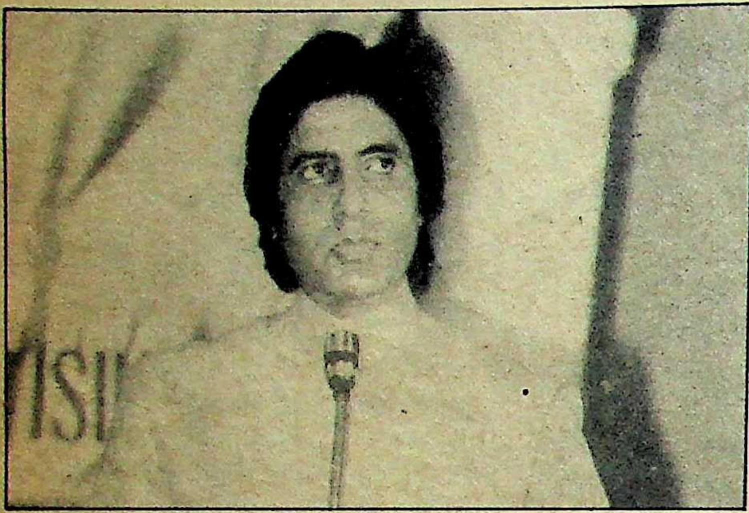

अमिताभ बच्चन

अब इसे संयोग कहिए या और कुछ, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री के साथ अमिताभ पिकनिक पर जाते हैं, किसी-न-किसी के 'तंबू में बंबू' लग ही जाता है। बंबई में कांग्रेस शताब्दी समारोह के बाद रणथम्भौर में जब दिल्ली दरबार ने अमिताभ के साथ 'न्यू ईयर ईव' मनायी थी, तो उसी के बाद अरुण नेहरू का पत्ता साफ होना शुरू हो गया था।

इसके बाद जब दिसंबर १९८६ की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नया वर्ष मनाने के लिए रंगून होते हुए अंडमान पहुंचे थे, तो भी अमिताभ बच्चन साथ थे। वहां से लौटते ही विदेश सचिव वेंकटेश्वरन की छुट्टी कर दी गयी। उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया।

इस बार दिल्ली दरबार ने लक्षद्वीप में 'न्यू ईयर ईव' बनायी। साथ में अमिताभ भी थे। लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ही हरिदेव जोशी पर गाज गिर पड़ी। उन्हें मुख्यमंत्री-पद से हटाकर शिवचरण माथुर को ताज पहना दिया गया।

अब सूचना मिल रही है कि राजीव गांधी राजाजी पार्क (देहरादून) में 'पिकनिक' मनाने जाने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गयी हैं। यदि इस पिकनिक में अमिताभ गये, तो हिट लिस्ट में किसका नाम चढ़ जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस आशंका से सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री और मंत्री भयभीत हो उठे हैं।

इस बीच, वीर बहादुर सिंह जो फिलहाल अमिताभ को भुलाकर पार्टी विधायकों की सेवा में लग गये थे; अब पुनः अमिताभ की ओर मुखातिब हो गये हैं। उन्होंने दिल्ली दरबार से कह दिया है कि इलाहाबाद से अगर कोई लोकसभा का चुनाव जीत सकता है, तो वह अकेले अमिताभ ही हैं। दिल्ली दरबार से उन्होंने आग्रह किया है, "अमिताभ को फिर से इलाहाबाद से खड़ा कर दीजिए, मैं उन्हें हर हालत में जिता दूंगा।"

नयी अटकल

दिल्ली के सत्ता-गलियारों में यह अजीबोगरीब खबर इन दिनों जोर पकड़ रही है कि बोफोर्स कांड में ली गयी दलाली की जानकारी राजीव गांधी को सचमुच ही नहीं थी। कहा जाता है कि बंबई के कांग्रेस शताब्दी समारोह में उन्होंने सत्ता के दलालों से पार्टी को मुक्त करने का जो आह्वान किया था, उससे पार्टी के वरिष्ठ नेता अत्यंत चिंतित हो उठे थे। उन्हें मालूम था कि प्रधानमंत्री का यह नया जोश राजनीतिक सचाइयों से दो चार होने पर जल्द ही छूमंतर हो जायेगा। अतएव पुरानी आदत से मजबूर उन्होंने राजीव गांधी की जानकारी के बिना ही दलाली की रकम वसूल कर पार्टी के स्विट्जरलैंड खाते में जमा कर दी। जब बावेला-बवंडर उठा और राजीव गांधी ने जांच-पड़ताल की, तभी इस कड़वी सचाई का उन्हें पता चला। किंतु यदि वह यह सचाई बेनकाब करते हैं, तो पार्टी मटियामेट हो सकती है। अतः उन्होंने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। कहा जाता है कि यह बात वह अपने निकट सहयोगी-मित्र और भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह से भी छिपाने को मजबूर थे। इस गलतफहमी का शिकार होकर कि शायद प्रधानमंत्री स्वयं इसमें शामिल हों, अरुण सिंह ने इस्तीफा दे दिया।

राजीव गांधी

प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां अपने करीबी सहयोगी की मित्रता खोयी, वहीं दूसरी ओर अपनी बेदाग छवि। शायद ईर्ष्यालु घाघ कांग्रेसी चाहते भी यही थे।

अंतुले की वापसी

अब्दुल रहमान अंतुले

महाराष्ट्र के राजनीतिक मंच पर एक नया समीकरण बनने की अफवाह जोरों पर है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक प्रभावशाली गुट अंतुले की वापसी और ताजपोशी के लिए रात-दिन एक किये हुए हैं। अंतुले के पक्ष में कई बातें गिनायी जाती हैं। मसलन अंतुले ने मुख्यमंत्री एस०बी० चह्वाण के पुत्र के चुनाव के मौके पर लगभग दो दर्जन सभाओं को संबोधित किया था। इसी प्रकार उन्होंने गुलाम नबी आजाद को चुनवाने में भी उनकी भरपूर मदद की थी। इसके अलावा अंतुले ने सत्ताच्युत होने के बाद से आज तक नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ कभी जबान नहीं खोली। कहा तो यहां तक जाता है कि इस मुहिम में प्रधानमंत्री की कार्यशैली से क्षुब्ध शरद पवार और वसंत दादा पाटिल भी अंतुले की वापसी के लिए प्रयासरत हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वरिष्ठतम नेताओं की वफादारी पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में शायद वफादार अंतुले की वापसी पार्टी के लिए कारगर सिद्ध हो। □

सिख रेजीमेंट

छाया : गिरीश श्री[illegible]स्तव

छाया : सुनील सक्सेना

हेलीकाप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा

२६ जनवरी भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक दिन है। पूर्व की भांति इस बार भी देश का ३९ वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में जहां जोशोखरोश के साथ मनाया गया, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यह उत्सव अपने पारंपरिक गौरव के चरम पर रहा। देश के कोने-कोने से लोग हजारों की संख्या में इस उत्सव में भागीदारी के लिए दिल्ली आये थे। इस बार के समारोह के मुख्य अतिथि थे—श्रीलंका के राष्ट्रपति जे०आर० जयवर्धने, जो ११० मिनट तक चलनेवाले समारोह को पूरे मनोयोग से देखते रहे। राजपथ पर हुए मुख्य समारोह में पहली बार राष्ट्रपति के रूप में रामस्वामी वेंकटरमन ने सलामी ली। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी सहित बडी संख्या में विदेशी राजनयिक भी परेड देखनेवालों में शामिल थे।

समारोह की शुरुआत श्रीलंका में शहीद हुए मेजर रामस्वामी परमेश्वर की पत्नी उमा परमेश्वर को उनके पति की बहादुरी पर (मरणोपरांत) परमवीर

चक्र और सियाचिन में साहस दिखाने के लिए नायक सूबेदार बानासिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित करके हुआ। अलंकरण समारोह के बाद गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हुई। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ से गुजरकर ११ किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके लाल किले पहुंची। परेड का नेतृत्व कर रहे थे—मेजर जनरल विनोद बधवार।

थलसेना का अर्जुन टैंक पहली बार राजपथ से गुजरा। वायुसेना का 'जगुआर' विमान भी परेड में शामिल था। १९८७ में स्वीडन से आयी १५५ मिमी रेंजवाली बोफोर्स तोप को भी इस बार परेड में शामिल किया गया था, जिसे लेकर राजीव गांधी पर अनेक आरोप लगाये गये। परेड के ऊपर से हेलीकाप्टरों ने गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरीं। परेड में तीनों सेनाओं की चुस्तदुरस्त टुकड़ियों के साथ अर्द्धसैनिक बलों के दस्ते भी शामिल थे। सशस्त्र सेना की टुकड़ियों के पीछे १६८ लोक-कलाकारों ने वाद्य यंत्रों पर मिली जुली धुन बजायी जिसे प्रसिद्ध सरोदवादक अमजद अली खां ने लयवद्ध किया था।

यद्यपि सभी प्रदेशों ने झांकियां नहीं भेजी थीं, लेकिन जितनी भी झांकियां प्रदर्शित की गयीं, वे अत्यंत मनोरम रहीं। इनमें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, केरल तथा गोवा की झांकियां नृत्य प्रधान थीं, तो मध्य प्रदेश

: गिरीश श्रीवास्तव

ा की झांकी

मणिपुर की झांकी

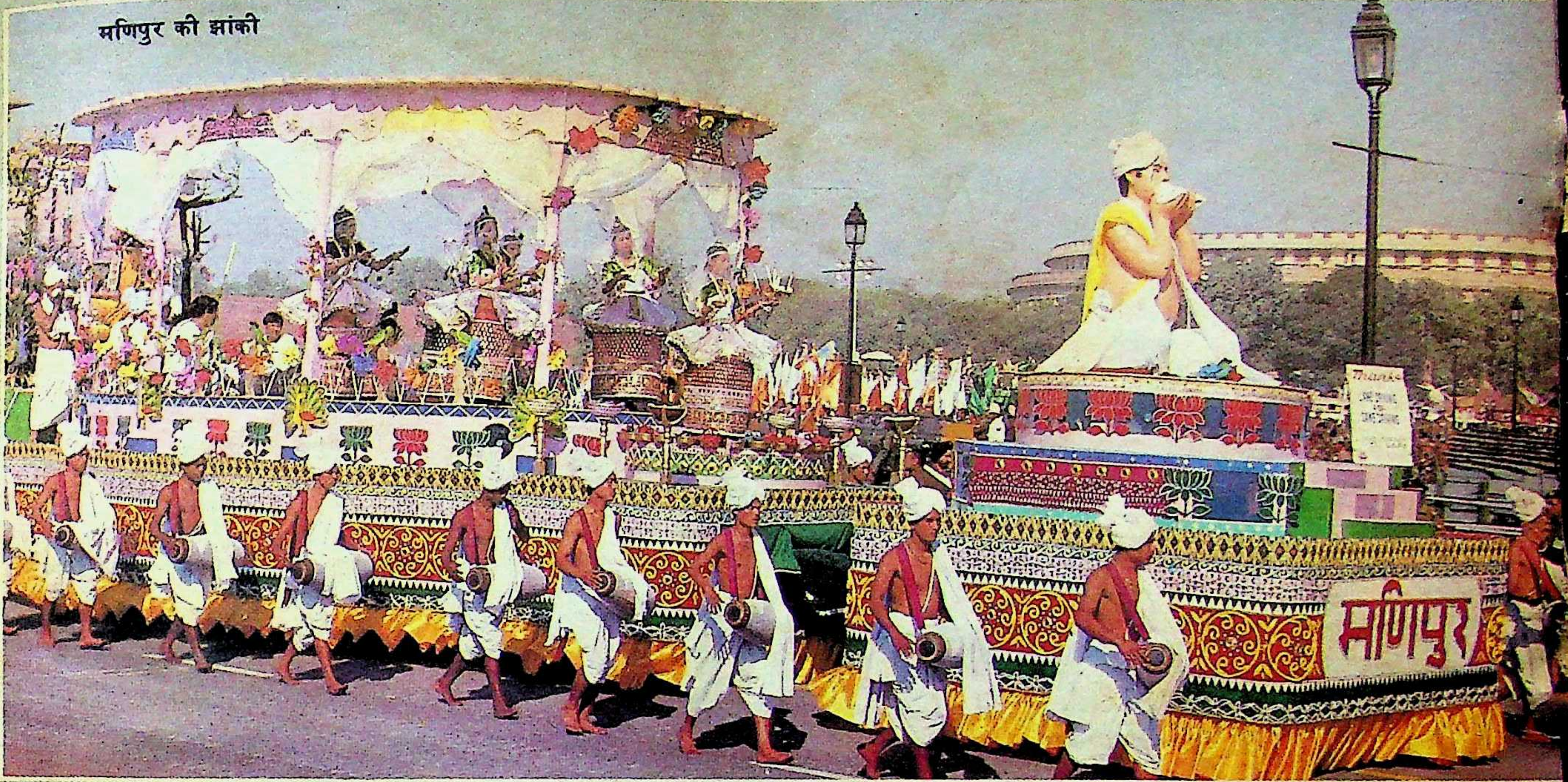

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

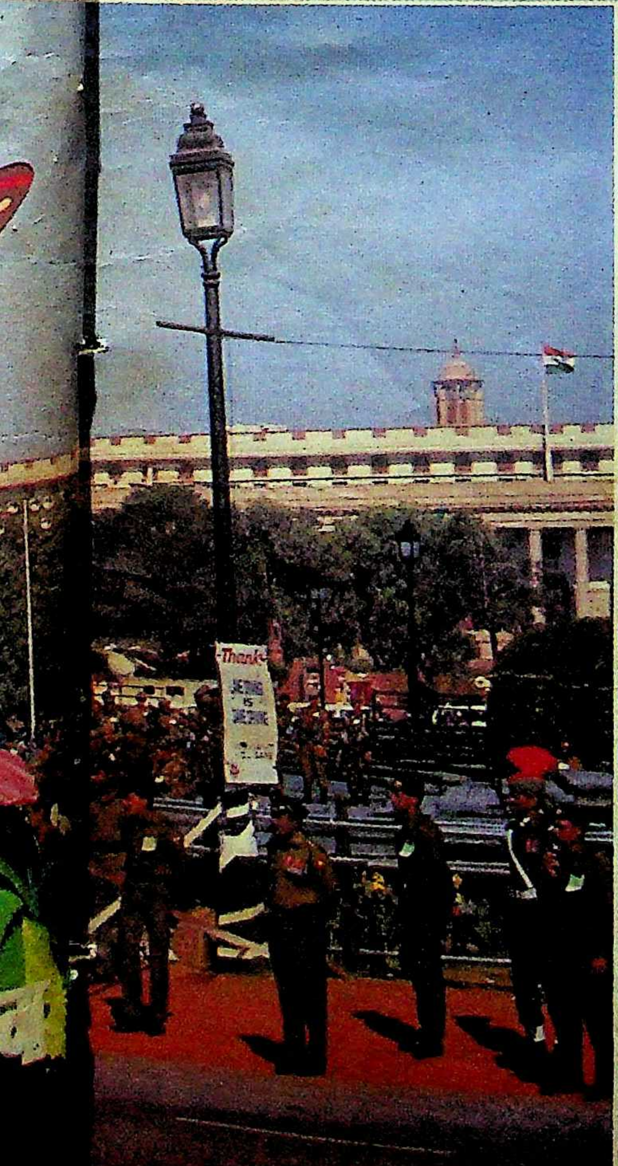

उत्तर प्रदेश की कत्यक-नृत्य की झांकी

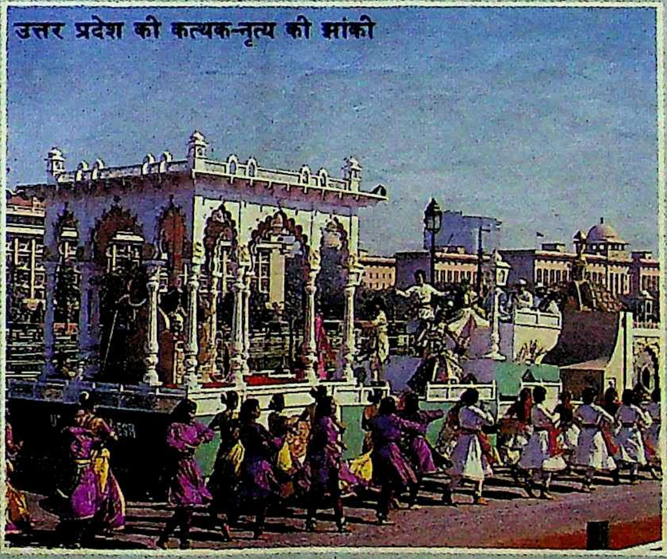

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

आंध्र प्रदेश की झांकी

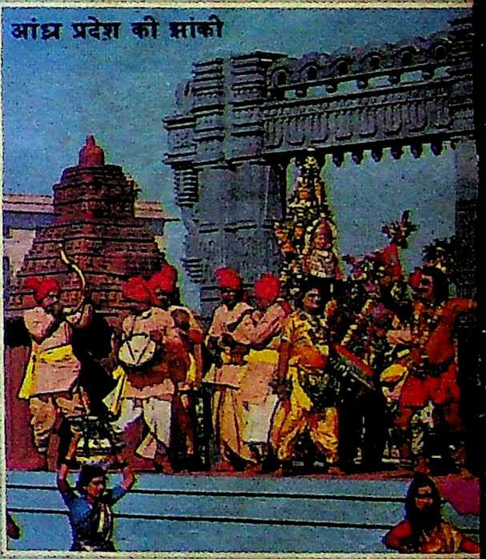

छाया : सुनील सक्सेना

बंगाल की झांकी

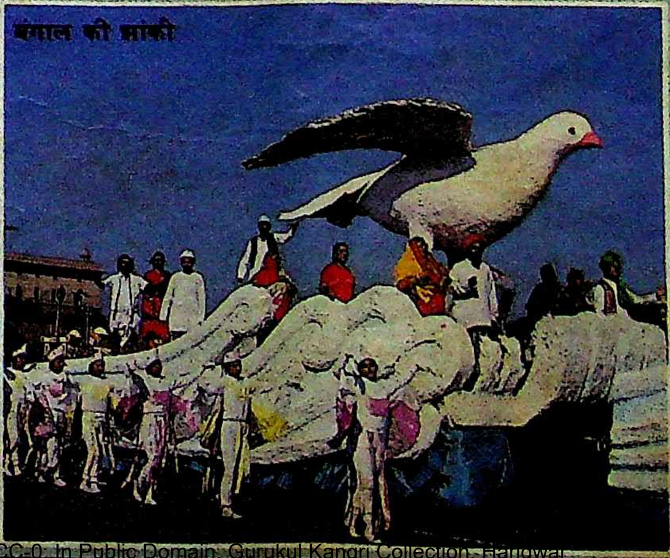

होली पर झांकी

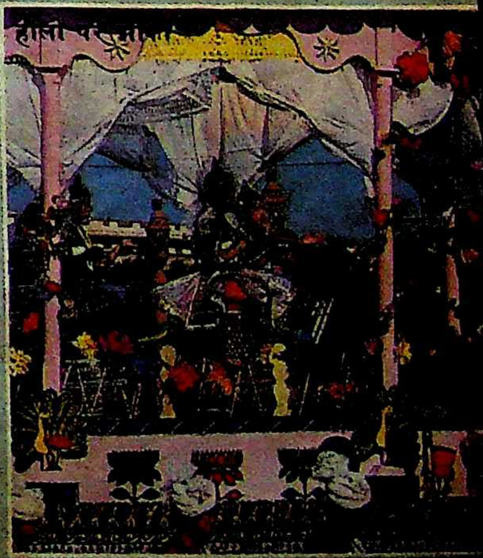

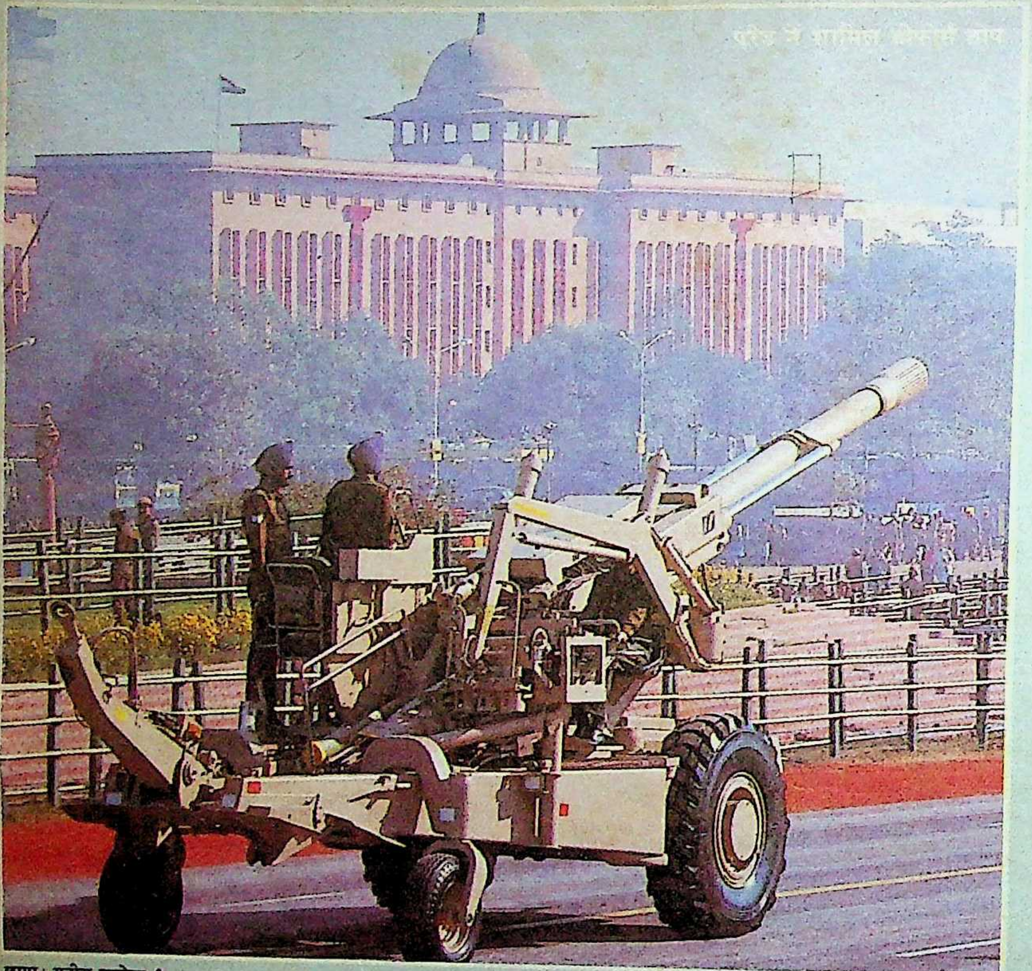

छाया : सुनील सक्सेना ▲

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, असम की झांकियां स्वतंत्रता संग्राम के अनेक पहलुओं पर थीं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा की झांकियों में इन प्रदेशों के जनजीवन और वहां की हस्तकलाओं को प्रदर्शित किया गया था। गोवा की झांकी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान पर रही, तो महाराष्ट्र की द्वितीय और मणिपुर और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहीं। सिख रेजीमेंट की टुकड़ी को प्रथम स्थान मिला।

मनोरम झांकियों के बीच उ०प्र० का विवादास्पद कत्थक नृत्य प्रदर्शित करती झांकी भी शामिल थी। प्रदर्शन के पूर्व इस झांकी पर कई विवाद उठे, जिस पर प्रसिद्ध कत्थक नर्तक बिरजू महाराज का कहना था कि कत्थक-नृत्य सड़कों पर प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। पर इसके बावजूद उ०प्र० सरकार की ओर से इस झांकी को परेड में शामिल किया गया। परेड में इस बार पहली दफा देश के मशहूर खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। ये खिलाड़ी तिरंगे ट्रैक सूट में थे—नेतृत्व कर रहे थे, 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह। परेड में हाथी पर वे २१ साहसी बच्चे सवार थे, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर पराक्रम दिखाया था।

▼ छाया : गिरीश श्रीवास्तव

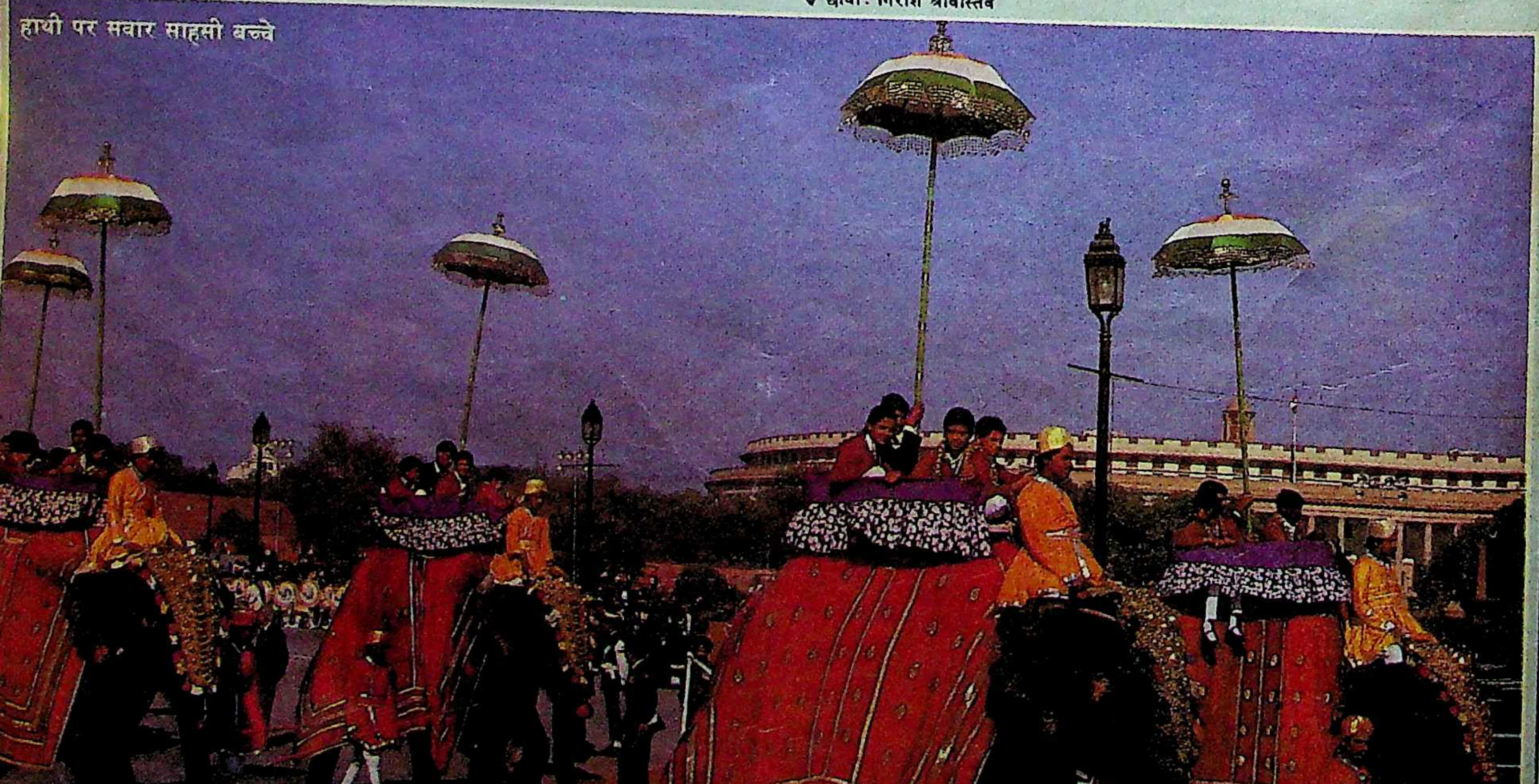
हाथी पर सवार साहसी बच्चे

प्राणलेवा लंकादहन

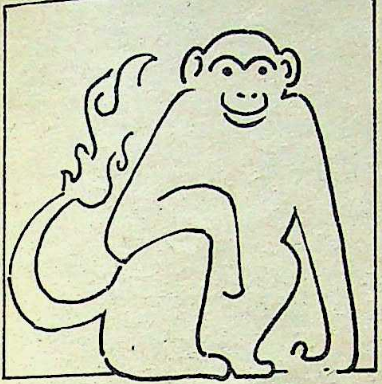

आधुनिक संदर्भों में कुछ लोगों द्वारा तुलसी का अवतार कहे जाने वाले फिल्मी निर्देशक रामानंद सागर ने जब से टीवी सीरियल 'रामायण' बनाया है तब से लोगों में वह इतना जनप्रिय हुआ है कि उसे देखे बगैर लोग रविवार को कोई काम ही नहीं कर पाते। दर्शकों ने इसे इतना पसंद किया है कि रविवार को यदि आप साढ़े नौ बजे सड़कों पर निकल जायें, तो बिलकुल कर्फ्यू-जैसा माहौल मिलेगा। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं कोई आपाधापी नहीं। लोग किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, 'रामायण' का जादू सभी के सिर पर चढ़कर बोलता है। यहां तक कि ग्वाला भी 'रामायण' के चक्कर में 'दूध दुहना' मुल्तवी कर देता है और कहता है बाबूजी रामायण के बाद आइये। बहराइच में तो दो शव-यात्राओं का समय मुल्तवी करना पड़ा। दोनों अंत्येष्टियों में जानेवालों ने मृतकों के घरवालों से कहा कि 'रामायण' देखने के बाद ही अरथी निकालना ठीक रहेगा। हुआ भी वही। जम्मू में तो एक रविवार को दर्शकों/भक्तों ने 'रामायण' के समय बिजली गुल हो जाने पर बिजली स्टेशन ही फूंक डाला। प्रयाग भी इसका अपवाद नहीं, यहां भी इसी चक्कर में चक्का जाम हो चुका है।

टीवी की पूजा तो यत्र-तत्र हो ही रही है, रामायण की शूटिंग-स्थली 'उमरगांव' आजकल तीर्थ हो गया है। आसपास के गांववाले वहां सुबह ही शूटिंग देखने पहुंच जाते हैं तथा राम, लक्ष्मण, सीता के पांव छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। एक सर्वेक्षण से तो यह भी ज्ञात हुआ है कि 'रामायण' के दिन गृहिणियां सुबह नाश्ते के बदले पूजा के आयोजन में लग जाती हैं। बाकायदा दीपदान, अगरबत्ती सुलगायी जाती है, फूल चढ़ाये जाते हैं, शंख बजते हैं। यों यह कोई नयी बात नहीं है। 'संतोषी मां' फिल्म जब लगी थी, तो हर शुक्रवार को टाकीजों में प्रसाद बांटा जाता था और दर्शक, खासकर-महिलाएं आरती करती थीं और साष्टांग दण्डवत करती थीं।

लेकिन यदि किसी के हृदय पर 'रामायण' के दृश्यों का इतना सांघातिक प्रभाव पड़े कि जान ही चली जाये, तो ताज्जुब तो होगा ही। किंतु ऐसी ही घटना बड़ोदरा में घट गयी। पता चला है कि पंचमहल जिले के हलोल तालुका में चंद्रपुरा गांव की दो महिलाएं 'रामायण' देख रही थीं। प्रसंग था—'लंका दहन'। इस लोमहर्षक दृश्य को देखकर दोनों महिलाओं में इतना भावातिरेक हुआ कि दोनों को एक ही साथ दिल का दौरा पड़ा और दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गये।

नये व्यंजन

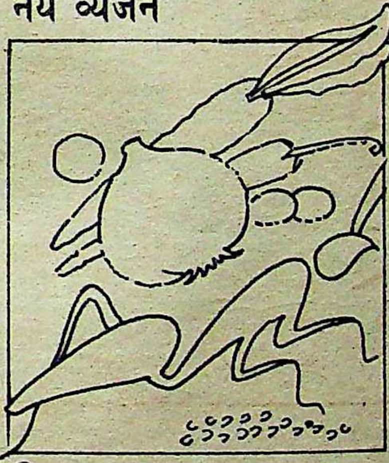

टिड्डियों और चींटियों का भी क्या खूब रिश्ता है मानव-समाज से। यों तो टिड्डियां पूरी-फसल-की-फसल चट कर जाती हैं, लेकिन चींटियों के लिए हमारे मन में बड़ा ही साधुता का भाव रहा है, बल्कि यों कहें कि चींटियों को चीनी मिला आटा खिलाकर हम अपने को परोपकारी मानते हैं, लेकिन थाईलैंड में आजकल टिड्डियां और चींटियां दोनों ही व्यंजन की श्रेणी में आ गयी हैं। आजकल वहां तली हुई कुरकुरी टिड्डियां, लाल चींटी के अंडों का हरी मिर्च, मूली, नीबू-घास और कतरी हुई लाल चींटियों के साथ मिलाकर बनाया गया 'चटपटा सलाद' और सफेद अंडों का काली मिर्च डालकर बांस की जड़ों के साथ तैयार किया गया स्वादिष्ट 'शोरबा' अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। यही नहीं वहां इसके लिए पाकशास्त्री और व्यंजन विशेषज्ञ भी हैं जो एक-से-एक वैज्ञानिक विधियां तलाशते रहते हैं। थाई सरकार को भी काफी राहत मिली है यह जानकर कि अब उसे टिड्डियों के उन्मूलन के लिए बेजा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन व्यंजनों पर अमरीकी व्यंजन विशेषज्ञों ने भी अपनी मुहर लगा दी है। वहां के भोजन-विशेषज्ञों के एक दल ने शोध के बाद पाया है कि ये कीट बहुत ही पौष्टिक हैं और ये प्रोटीन के स्रोत हैं।

अद्भुत भेंट

यह देश कुरबानियों एवं बलिदानों का देश है। यहां के देवी-देवता अपने भक्तों के उत्सर्ग से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त भी कुछ इतने देववत्सल हैं कि देवताओं को खुश करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, शरीर के अंगों-उपांगों की क्या बात? राजा शिवि को तो अपने शरीर की बोटियां देकर दानी होने का प्रमाण देना पड़ा। जिब्रील अलैस्सलाम ने तो अपने फूल जैसे बच्चे की कुरबानी कर डाली। लेकिन ये सब कथाएं बीते वक्त की बातें हो गयी हैं। आज हम सैटेलाइट युग में पहुंच गये हैं। कहने को बहुत विकसित भी हो गये हैं, लेकिन सच मानिये हमारी भावनाएं बदली नहीं हैं। इसी का ताजा दृष्टांत देखने को मिला है कर्नाटक में। बीजापुर जिले में कृष्णा और मलप्रभा नदियों के संगम पर स्थित प्रसिद्ध संगमेश्वर मंदिर में गुलबर्ग निवासी बासवनप्पा ने अपने शरीर की चमड़ी से बनी पादुकाएं भेंटस्वरूप चढ़ायीं और तीन दिवसीय 'शरण' मेले का उद्घाटन भी किया। कहते हैं, विगत ८०० वर्षों के इतिहास में यह दुर्लभ क्षण दूसरी बार आया है जब किसी भक्त ने अपने शरीर के चर्म की पादुकाएं मंदिर में अर्पित की हों। इससे पूर्व १२ वीं सदी में हरलय्या नामक मोची ने ऐसी भेंट चढ़ायी थी। इसे हम चाहे सच्ची भक्ति कहें या धर्मांधभक्ति बासवनप्पा ने तो कर दिखाया ही है।

फलतोड़क रोबोट

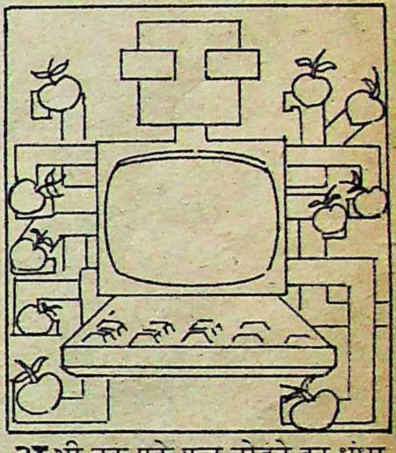

अभी तक पके फल तोड़ने का धंधा हमारे यहां कुजड़े और खटिक जाति के लोग करते रहे हैं और आकाशगामी पेड़ों पर चढ़कर फलों के तोड़ने का जोखिम उठाते रहे हैं। कितने तो पेड़ों से गिरकर स्वर्ग तक सिधार गये हैं, लेकिन अब इन लोगों की परेशानियां अमरीकी वैज्ञानिकों ने १२ हाथोंवाले यांत्रिक मानव (रोबोट) का आविष्कार कर खतम कर दी हैं।

यह कंप्यूटरीकृत रोबोट स्वयं पेड़ पर चढ़ेगा और बिना चखे केवल पके फलों को तोड़ेगा और स्वयं नीचे भी उतर आयेगा। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के खाद्य एवं कृषि विज्ञान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डा० आर०सी० हारसेल ने बताया है कि इस समझदार रोबोट की बांह के एक सिरे पर एक रंगीन टेलीविजन कैमरा होगा जो पके फल के पास पहुंचने पर गहरे नारंगी रंग का संकेत देगा। पके फल की जानकारी के बाद रोबोट की बांह उसकी ओर बढ़ेगी और फल तोड़कर टोकरीनुमा डब्बे में इकट्ठा करती जायेगी। मालूम रहे कि इसके पहले फलों को तोड़ने के कई यंत्र बनाये गये, लेकिन पके फलों को चुनने वाला यह सबसे पहला यंत्र है। अब देखना है कि अमरीका से यह यांत्रिक मानव भारत में कब पदार्पण करता है और कुजड़ों तक पहुंच भी पाता है या नहीं।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

दंगों की अंधेरी कोठरी और 'तमस'

आम आदमी, जिसे सांप्रदायिक तत्व इस्तेमाल करते हैं: 'तमस' के एक दृश्य में करमो (दीपा साही), सरदार हरनाम सिंह (भीष्म साहनी), बंतो (दीना पाठक)

दूरदर्शन के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोई सीरियल राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का मुद्दा बना है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस सीरियल को लेकर बावेला मचा है, वह विख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास पर इसी नाम से बना सीरियल है। उपन्यास डेढ़ दशक पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर यह आरोप कभी नहीं लगाया कि इसमें इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया है। फिर क्या कारण है कि जिस सीरियल का उद्देश्य सांप्रदायिकता की बुनियाद को पहचानने के लिए बना है, उस सीरियल को सांप्रदायिक करार दिया जा रहा है? सीरियल की कथावस्तु, कलापक्ष और इस पर उठे विवाद का विश्लेषण कर रहे हैं, **रवींद्र श्रीवास्तव**:

> *"आजादी के ठीक पहले का पंजाब और सांप्रदायिक वहशत के अंधेरे में डूबे वे चंद दिन... धार्मिक जड़ता को इस्तेमाल करती पूंजीपरस्त राजनीति और उससे लहूलुहान हजारों बेकसूर लोग...सूअर और गाय को बचा लेने का पुण्य और उसी के लिए होती हुई मनुष्य-हत्याएं...परदे के पीछे दंगा कराने वाले दिमाग और रूबरू कटते मानव-शरीर। ...यह एक माहौल है, जिसे 'तमस' में प्रस्तुत किया गया है।"*

यह विडंबना ही है कि जिस कृति का सृजन सांप्रदायिकता के नासूर को निर्मूल करने के उद्देश्य से हुआ और जिस सीरियल का शीर्षक उद्धरण यह कहता हो कि जो इतिहास को भूलने की कोशिश करते हैं, वे उसको दुहराने के लिए अभिशप्त हैं, उसी कृति पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह सांप्रदायिकता फैलाने वाली है।

भारत में विभाजन की विभीषिका पर 'गर्म हवा' (एम०एस० सथ्यु) तथा 'नास्तिक' (ऋत्विक घटक) आदि कुछ ही फिल्में बन सकीं। यशपाल, मंटो आदि जिन कुछ लेखकों ने इसे विषय बनाकर उपन्यास-कहानियां लिखीं, उनमें से एक हैं भीष्म साहनी. लेकिन अन्य हिंदी कृतियों की तरह उनका उपन्यास 'तमस' भी 'बेस्ट सेलर' नहीं बन सका, फलतः कुछ हजार पाठकों के हाथों तक ही पहुंच कर कैद रह गया।

१९८० में प्रयोगधर्मी फिल्मकार गोविंद निहलाणी ने 'तमस' जब पहली बार पढ़ा, तभी इस पर फिल्म बनाने का निश्चय किया, किंतु 'विजेता', 'आक्रोश', 'अर्द्धसत्य', तथा 'आघात' जैसी छोटी बजट वाली फिल्मों के निर्माण-निर्देशन से जुड़े रहने के कारण अपने आपको वह 'तमस' पर पूरी तरह केंद्रित नहीं कर पाये, लेकिन पेपर वर्क (कथा-पटकथा-संवाद) चलता रहा। १९८६ में उन्होंने 'तमस' का निर्माण काफी गोपनीय ढंग से शुरू किया और शूटिंग स्थल को वर्जित क्षेत्र घोषित कर प्रेस और बाहरी संसार से उसे न केवल अलग-थलग रखा, बल्कि खुद और फिल्म के सभी कलाकारों-तकनीशियनों को भी 'तमस' के बारे में बोलने से बरज दिया।

व्यथित नत्थू (ओमपुरी)

अपूर्व दस्तावेज : 'तमस' रिचर्ड एटनबरो की 'गांधी' तथा रमेश सिप्पी की 'बुनियाद' (प्रारंभिक कुछ एपीसोड) के बीच का सेतुमंच है। 'गांधी' एक महान व्यक्ति और उनके आस-पास के परिवेश से जुड़े हुए लोगों की जीवन-कथा थी, लेकिन रमेश सिप्पी की 'बुनियाद' मेलोड्रामा था। उसके पात्र, वातावरण तथा माहौल भी नकली लगते थे, लेकिन 'तमस' एक दस्तावेज है—इतिहास के एक ऐसे अध्याय का जिसके दर्द से आज भी समूची मानसिकता निजात नहीं पा सकी है। स्वतंत्रता से पूर्व एवं विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में ५ लाख से अधिक हिंदुओं-मुसलमानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और लगभग दो करोड़ लोग बेघरबार तथा इस भयानक हादसे के शिकार हुए थे। इस प्रकार के जातीय विद्वेष से उपजा हादसा संभवतः किसी देश में इसके पूर्व नहीं हुआ था, जब लोग एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती, इंसानी रिश्ते और पड़ोसी के धर्म को भूलकर अचानक ही एक-दूसरे के खून के प्यासे हो उठे हों। उन्हीं के बीच बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर दूसरे संप्रदाय के लोगों की जान बचाते फिर रहे थे।

'तमस' इसी हादसे और ऐसे ही लोगों की फिल्म है, जो बड़ी बेबाकी से एक तरफ तत्कालीन राजनीति, दलगत एवं जातिगत अलगाव के खूंख्वारपने और व्यक्तिगत स्तर पर उतर आयी बड़े, नेताओं की कूटनीति की विषबेलि के जज्बे को बड़ी बेबाकी से बेनकाब करती है, तो दूसरी तरफ उस जमाने के माहौल, आम लोगों की मानसिकता के विविध पहलुओं और भीतर-ही-भीतर पनप रही अलगाव की भावना को पर्त-दर-पर्त उधेड़ती है।

उपन्यासकार भीष्म साहनी सांप्रदायिक दंगों एवं हिंदुओं-मुसलमानों के भाई-चारे की जिंदगी में जहर घोलने की साजिश अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' कूटनीति को मानते हैं। उपन्यास की शुरुआत में उन्होंने अंग्रेज हुक्मरानों की इस चाल का परदाफाश किया है। फिल्म 'तमस' की शुरुआत जानवरों की खाल उतारनेवाले नत्थू चमार (ओम पुरी) को एक सूअर की हत्या करने के लिए सरकारी ठेकेदार मुराद अली (पंकज कपूर) द्वारा राजी किये जाने के दृश्य से होती है कि सलोतरी साहब को अस्पताल में किसी प्रयोग के लिए सूअर की लाश चाहिए। सरकारी ठेकेदार और उसके गोरे साहब, जिसका फिल्म में इतने संक्षिप्त रूप में जिक्र हुआ है कि दंगों के [illegible] नहीं पाते। साजिश और संभावित परिणामों से अनजान नत्थू सूअर मार कर उन्हें दे देता है। सुबह मस्जिद के सामने पड़ी सूअर की लाश मुस्लिम लीग की 'पाकिस्तान लेने' तथा विभाजन की संभावनाओं के कारण पहले से ही गर्म (छोटे से शहर जलालाबाद के) माहौल में तुर्शी ला देती है। जवाबी कार्रवाई में मंदिर के सामने एक गाय की लाश पड़ी मिलती है। सूअर और गाय की हत्याओं का दौर अचानक दंगे, लूटपाट, आगजनी और दोनों संप्रदायों के लोगों की नृशंस हत्याओं में बदल जाता है जिसका अंत होता है दंगे में पतियों-भाइयों के शहादत पा लेने पर दर्जनों महिलाओं द्वारा कुएं में कूद कर सामूहिक आत्महत्या कांड से।

केंद्र बिन्दु : 'तमस' एक साथ कई केंद्र बिंदुओं के इर्द-गिर्द घूमती है। एक केंद्र बिंदु है—नत्थू चमार, जो इस समूचे कांड का जिम्मेदार खुद को मानकर आत्मग्लानि और संशय की भावना से इस कदर ग्रस्त है कि दिन भर इधर-उधर भटकता रहता है और गर्भ के ८वें महीने में चल रही उसकी पत्नी करमो (दीपा साही) तथा वृद्धा मां शहर की गर्म हवा के कारण बेचैन रहती हैं। आत्मग्लानि के अंतिम चरण में वह मन की घुटन करमो के सामने खोल पाता है और अंततः वह उसे संतोष देती है—तूने जान बूझकर सूअर मारकर तो मस्जिद के बाहर नहीं फेंका। तेरा तो धंधा है जानवर मारने या उसकी खाल उतारने का, तूने अपना काम कर दिया। गुनहगार तू नहीं वह है जिसने तुझसे यह काम करवा कर मस्जिद के सामने सूअर की लाश फिकवा दी। दूसरा केंद्र है राजनीतिक दलों का स्थानीय स्वरूप। कांग्रेसी नेता बख्शीजी (ए०के० हंगल) कांग्रेसी स्वयंसेवकों के साथ प्रभात फेरी के लिए मुसलमानों के मुहल्ले में जाकर गंदगी की सफाई करते हैं, जहां उनका टकराव होता है 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाते मुस्लिम लीग के नेता हकीम हयात बख्श (मनोहर सिंह) और उनके साथियों से। तीसरा केंद्र बिंदु है, हिंदू महासभा और संभावित खतरे से सुरक्षा के लिए उनकी तैयारियों, किशोरों को गणवेश की दीक्षा देकर उन्हें हिंदुत्व की रक्षा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया और इन सबकी पृष्ठभूमि में जागरूक व्यवसायी समाज। इनका प्रतिनिधित्व करते हैं लाला लक्ष्मीनारायणजी (हरीश पटेल)। चौथा केंद्र बिंदु है, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड हैमिल्टन (बेरी जान) तथा उसकी पत्नी लिजा (केरेन स्मिथ)। रिचर्ड को भारतीय पुरातत्व सामग्रियों से इतना मोह है कि अपने संग्रह को वह अपनी पत्नी लिजा तक को छूने नहीं देता, लेकिन मानसिक तौर पर वह सिर्फ अंग्रेज हुक्मरान है, आम अंग्रेज शासकों का प्रतीक। दंगे को रोकने के लिए नेता और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की गयी अपील को वह बड़ी सहजता से 'यह आप लोगों की फैलायी हुई समस्या है' कह कर प्राचीन भारतीय पोथियों के अध्ययन में जुट जाता है, लेकिन उसकी पत्नी लिजा दंगों में हताहतों की सेवा में जुट जाती है। पांचवा केंद्र बिंदु है, वे लोग जो सांप्रदायिक दंगे और अलगाव की

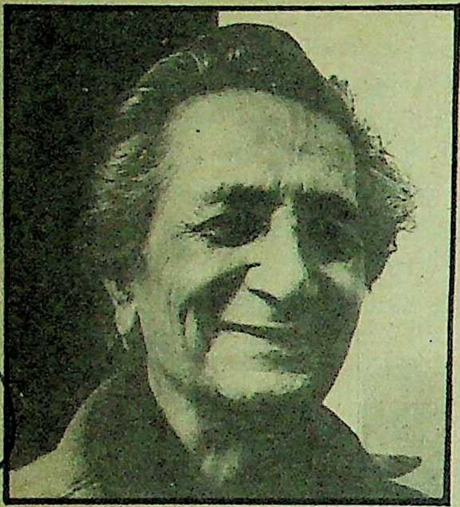

साक्षात्कार/**भीष्म साहनी**

धारावाहिक और उपन्यास में कहीं भी दृष्टिभेद नहीं है

विनम्र, विनीत, मृदुभाषी व्यक्तित्व यह आभास नहीं देता कि वही उस कृति के रचयिता हैं, जिस पर बना धारावाहिक दूरदर्शन के इतिहास में पहली बार देशव्यापी प्रचंड समर्थन-प्रतिरोध, उत्सुकता-उत्कंठा का केन्द्र बिन्दु बन गया है। ८ कहानी संग्रह, ५ उपन्यास, ३ नाटक, एक जीवनी के प्रख्यात लेखक, 'मोहन जोशी हाजिर हों' फिल्म के नायक, लगभग ६० वर्षीय भीष्म साहनी अपने बड़े भाई स्वर्गीय बलराज साहनी जैसे शीर्ष कलाकर्मी ही नहीं, प्रतिबद्ध वामपंथी भी हैं। 'तमस' संबंधी विवाद पर पहली बार उन्होंने 'माया' से विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

माया : धारावाहिक में आपके उपन्यास की मूलभावना का कहां तक निर्वाह हुआ है?

साहनी : प्रख्यात निर्देशक गोविंद निहलाणी ने मेरे उपन्यास के दृश्य व श्रुति बोध का सम्यक विस्तार करके तत्कालीन परिवेश का अटूट-अक्षत उद्‌घाटन किया है। किसी कृति के फिल्मांकन की कसौटी है लेखक और निर्देशक में वैचारिक और संवेदनात्मक संतुलन व तालमेल। इस दृष्टि से इस धारावाहिक व उपन्यास में कहीं भी दृष्टिभेद नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके फिल्मांकन से भी जुड़ा हूं। इसमें मेरी एक भूमिका भी है जिसे आगामी शृंखलाओं में आप देखेंगे। मेरा मत है कि इस धारावाहिक में उपन्यास की मूलभावना पूर्णतया सजीव और सुसंगत रूप में विद्यमान है।

माया : इस धारावाहिक का व्यापक हिंदू-मुस्लिम संगठनों द्वारा इतना जबर्दस्त विरोध क्यों हो रहा है?

साहनी : मेरे लिए भी यह एक प्रश्न बना हुआ है। 'तमस' १९७४ में प्रकाशित हुआ। अगले वर्ष ही इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनेक विश्वविद्यालयों में यह उपन्यास लगा हुआ है। अंग्रेजी सहित कुछ भारतीय भाषाओं मसलन कन्नड़, उर्दू, पंजाबी में यह प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त नेशनल बुक ट्रस्ट इसे तमिल, बंगला, गुजराती आदि चार भाषाओं में प्रकाशित करने का अनुबंध भी मुझसे कर चुका है। इस प्रकार 'तमस' के प्रकाशन के १३ वर्ष बाद यह मुद्दा इस रूप में उभारना अजीब सा लगता है।

माया : कुछ पार्टियां व संगठन इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और इतिहास की गलत व्याख्या करने वाला धारावाहिक बता रहे हैं।

साहनी : धारावाहिक के प्रारंभ में ही बयान देकर 'तमस' के कथ्य और उद्देश्य को मैं स्पष्ट कर चुका हूं। उपन्यास में मैंने विभाजन पूर्व काल में सांप्रदायिक सोच वाले निहित स्वार्थों की अमानवीय घृणा, क्षुद्रताजन्य भेदभाव और रक्तपिपासु वृत्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। इतिहास के सिंहद्वार से निकले इन चरित्रों को अनदेखा करना दंगा, हिंसा व विभाजन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। किंतु 'तमस' में इन चरित्रों के बावजूद विभिन्न संप्रदायों के मूक बहुसंख्य लोग शांति, भाईचारा और प्रेम के पक्षधर के रूप में उभरे हैं। इस प्रकार यह मात्र अंधेरे की कथा नहीं, महान भारतीय आदर्श 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'—अंधेरे से उजाले की यात्रा की एक कथा है। इतिहास नाम-तिथि और घटनाओं का रोजनामचा मात्र नहीं होता, बल्कि व्यापक जीवन को आंदोलित-चालित-प्रेरित करने वाला एक सिलसिला होता है जो अंतर्भूत सत्य को उसके विविध आयामों सहित उद्‌घाटित करता है। मैंने अपने उपन्यास में भी इतिहास की इसी समझदारी को उजागर करने की कोशिश की है। सांप्रदायिकता ऐसा संक्रामक रोग है जो छिपाने से और बढ़ता-फैलता और भयावह बनता है। इसके इलाज की पहली शर्त है इसकी सही पहचान। सांप्रदायिक तत्वों, भले ही वह बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, को अनदेखा करना उनके पुनः आगमन को दावत देना होगा।

माया : यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू सांप्रदायिकता को जितनी शिद्दत के साथ उभारा गया है उससे अधिकांश लोग खुश नहीं हैं।

साहनी : सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से नहीं कट्टरता, मूढ़ता और गलत समझदारी से है। उपन्यास व धारावाहिक में कोई ऐसा भेदभाव या वर्गीकरण नहीं। समतामूलक मानवीय दृष्टिकोण, व्यापक सामाजिक सरोकार और सतत राष्ट्रीय उन्नयन को मद्देनजर रख इस बात पर बल दिया गया है कि मजहबी दंगे-फसाद से संपूर्ण समाज और राष्ट्र क्षत-विक्षत, विभाजित होता है। फिर धारावाहिक के आधे-अधूरे भाग को देखकर ऐसी संकुचित धारणा बनाना क्या उचित है?

जहां तक धारावाहिक का आम दर्शकों से संबंध है उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं अड़ोस-पड़ोस, सड़क-बाजार जहां भी जाता हूं लोग धारावाहिक को लेकर प्रशंसा ही व्यक्त करते हैं, विरोध या खिन्नता नहीं। इस संबंध में विभिन्न संप्रदाय व वर्गों के लोगों व खासकर नयी पीढ़ी के दर्शकों-पाठकों के अनेक मार्मिक पत्र भी आये हैं जिससे मैं अभिभूत हूं।

माया : 'तमस' की रचना करते समय क्या उद्देश्य आपके सामने था तथा उसकी पूर्ति में यह धारावाहिक कहां तक सहायक हुआ है?

साहनी : विभाजन आधुनिक भारतीय इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे जैसा फैला है। प्रत्येक देशप्रेमी और सुधी नागरिक जानता-समझता है कि इस शर्मनाक घटना से देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, कितने बेकसूर नर-नारियों का कत्लेआम हुआ, नफरत और दीवानगी का कैसा घना, भयावह अंधेरा छाया। हमें ऐसी वारदातों के प्रति पूर्णतया सचेत, सजग और लामबंद होना चाहिए। एक लेखक के नाते ईमानदारी से सत्य का पक्षधर हो, अपनी लेखनी द्वारा मैं अपने पाठकों को सांप्रदायिकता, अलगाववाद के विषाक्त माहौल से सचेत करूं और सामान्य जन की भरीपूरी, खुशहाल अमनचैन की, बिरादराना जिंदगी का ख्वाब बुनूं यही उद्देश्य लेकर मैंने 'तमस' की रचना की थी। विडंबना यह है कि मेरी जो कृति सांप्रदायिक एकता, सौहार्द्र के उन्नयन में सहायक होने के नाते पुरस्कृत हुई उसी पर बने धारावाहिक को मुट्ठी भर संगठन व लोग सांप्रदायिकता भड़काने वाला करार दे रहे हैं। किंतु मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि सत्य, प्रेम और भाईचारे के पक्षधर लाखों लोग इसे देखने को बड़ी बेकरारी से प्रतीक्षा करते हैं। मुझे आशा है, धारावाहिक अपने समग्र रूप में दर्शकों के सम्मुख अपनी संपूर्ण सार्थकता, प्रभावमयता और अर्थवत्ता के साथ उजागर होगा।

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

धर्मों में बंटे लोग: हकीम हयात बख्श (मनोहर सिंह), लालाजी (हरीश पटेल), बख्शीजी (ए०के० हंगल)

राजनीति में विश्वास नहीं करते और दोनों संप्रदायों में एकता के लिए प्रयास करते हैं। इसका पक्षधर है कवि जहूर बख्श (अशोक बांठिया) जिनके पास गीता, महाभारत, शाकुंतल, रामायण, मेघदूत आदि ग्रंथों का संकलन है और हिंदु संप्रदायवादियों द्वारा दंगे के समय इन्हें जलाने से रक्षा करने में अपनी जान दे देता है। मुसलमान राजो (सुरेखा सीकरी) जो बंतो (दीना पाठक) तथा उसके पति सरदार हरनाम सिंह (भीष्म साहनी) की न केवल अपने दंगाई खाविंद और बेटे से रक्षा करती है, बल्कि उनके शिकंजे से उन्हें सुरक्षित निकालने के साथ-साथ उनकी बंदूक और गहने वापस कर देती है, जिसे उसकी पुत्र-वधू ने उनके सूटकेस से चुरा लिया था। जसबीर कौर (उत्तरा बावकर) जो अपने मुसलमान अध्यापक किरायेदार की बलवाइयों से रक्षा के लिए तलवार तानकर उनके सामने आ जाती है—यह मेरा भाई है, अगर किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की, तो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूंगी, रबाबी गायकवृंद जो गुरुद्वारों में शबद-कीर्तन करते हैं, लेकिन दंगे के कारण गुरुद्वारे का द्वार अपने लिये बंद पाकर सबसे अधिक क्षुब्ध हैं, प्रगतिशील मीरदाद (के०के० रैना) जो दंगे के गर्म वातावरण के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पहुंचने के लिए हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। उस समूचे तटस्थ जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं कम्युनिस्ट नेता इकबाल (एम०के० रैना), जो हिंदुओं-मुसलमानों के बीच सुलह कराने के लिए एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कट्टर नेताओं के बीच की खाई पाटने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ सभी दलों के नेताओं, प्रमुख व असरदार व्यक्तियों की मीटिंग कलेक्टर के साथ कराकर तुरंत अमन-चैन कायम करने के लिए बेकरार हैं। वे जानते हैं कि अगर एक बार फौज शहर में मार्च पास्ट कर जाये, तो दंगे खतम हो जायें।

इन छहों केंद्र बिंदुओं के बीच मुख्य कथा इन्हीं वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ चलती है। मुस्लिम बहुल इलाके में रहनेवाले हिंदू महासभाई लालाजी (हरीश पटेल) और उनके परिवार को सुरक्षित उनके बड़े भाई के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है उनका दोस्त शाहनवाज खान, लेकिन एक मुस्लिम जनाजे को देखकर अपना आपा खो बैठता है और लालाजी के निरपराध अल्प विकसित मस्तिष्क वाले नौकर की हत्या करने से अपने को रोक नहीं पाता।

कहानी का प्रथम चरण सांप्रदायिक दंगा शुरू होने से पहले की पृष्ठभूमि है। दोनों संप्रदायों के बीच नफरत के दबे-छिपे जहर को गोविंद निहलाणी विभिन्न पात्रों के माध्यम से पेश करते हैं। एक तरफ मास्टर देवव्रत (एस०पी० दुबे) किशोरों में हिंदुत्व की रक्षा के प्राण फूंकते हैं, लालाजी के कमजोर-मन पुत्र रणवीर (रिज्जू बजाज) से एक मुर्गी हलाल करवाकर उसे मानसिक धरातल पर इस कदर शूरवीर बना देते हैं कि एक इत्र वाले की वह हत्या करने तक से नहीं झिझकता। दूसरी तरफ मस्जिद में दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध होनेवाली सभाएं गर्म हो उठती हैं और इसका जवाब हत्या तथा बाजार को आग लगाकर देती हैं।

फिल्म का दूसरा चरण सांप्रदायिक दंगे की आग में जल रहे जलालाबाद, राजनीतिक दलों की आपसी सौदेबाजी और अमन चैन कायम करने के सामूहिक प्रयासों का है, जिसमें जनसेवा का भाव उतना प्रखर नहीं है जितना मौकापरस्ती और अपने तथा अपनें दल के पैर जमाने की कोशिशों का है। तीसरा चरण दंगे के शिकार आम लोगों के शहर से पलायन का है। चौथा चरण किले के रूप में परिणत हो गये गुरुद्वारे का है जहां नत्थू, सरदार हरनाम सिंह जैसे तमाम दंगा-पीड़ितों ने पनाह ले रखी है। गुरुद्वारे के भीतर अरदास, शबद-कीर्तन चल रहा है और छत पर हथियारबंद लोग पहरा दे रहे हैं। आतंक भरे माहौल व शबद-कीर्तनों के बीच एक चेहरा उभरता है—मुख्य ग्रंथी सरदार तेजा सिंह (अमरीश पुरी) का, जो अपनी अथाह संपति के बावजूद, दंगाइयों की गुरुद्वारे के भीतर लोगों को बख्श देने के लिए २ लाख रुपए की मांग पूरी करने के लिए औरतों-पुरुषों से उनके जेवर तथा रुपए मांगते हैं, लेकिन रुपए कम पड़ जाने पर अपने पास से बतौर कर्ज भी लगाने के लिए तैयार नहीं। दंगाइयों से बात करने के लिए वह बजाय खुद जाने के सहायक ग्रंथी को भेजते हैं और उसके साथ जाने के लिए चुनते हैं नत्थू को, जो अपनी गर्भवती बीवी की क्षण-प्रतिक्षण गिरती हालत से पहले ही अधमरा हो चुका है। बाहर से आये दंगाइयों के बीच सहायक ग्रंथी और नत्थू के फंस जाने पर किले के भीतर महिलाओं-बच्चों की रक्षा के लिए तथा उन्हें (बलवाइयों) गुरुद्वारे के भीतर घुसने से रोकने के लिए सभी पुरुष हथियारों के साथ गुरुद्वारे से निकल पड़ते हैं और भीतर महिलाएं अरदास करने लगती हैं। अरदास कर रही प्रमुख महिला को अरदास के दौरान कुरबानी के हुक्मनामे का अहसास होता है और वह सभी युवतियों-किशोरियों-बच्चों को लेकर पास के कुएं पर जाकर कुएं में कूदकर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेती हैं ताकि वे बलवाइयों के हाथ नहीं लग सकें।

'तमस' में मेलोड्रामा नहीं है, इसलिए स्थितियों का विकास नाटकीय घटनाओं के साथ नहीं, बल्कि माहौल व सिचुएशंस के साथ होता है। घटनाएं एक-दूसरे के साथ स्वतः जुड़ती हैं, कथा से जुड़ते चरित्रों के साथ कहानी निर्बाध गति से बढ़ती है। फिल्म का प्रथम भाग (दंगे की शुरुआत) विभिन्न घटनाओं, प्रकरणों तथा विविध चरित्रों के साथ विकसित होता है—कभी कांग्रेसी बख्शीजी, मुस्लिम लीगी हकीम हयातबख्श, तो कभी लालाजी, उनके पुत्र रणवीर, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर दंपति तथा दूसरे छोटे चरित्रों-प्रकरणों के माध्यम से कथा किस्सागोई के अंदाज में बहती है फिर दूसरे भाग में कथा की मुख्य धारा से जुड़ जाती है—एक तरफ अपनी प्रसवपीड़ित गर्भवती पत्नी, बीमार बूढ़ी मां के साथ भाग रहा नत्थू, सरदार हरनाम सिंह एवं बंतो तथा उन जैसे ही तमाम पलायन कर रहे हजारों-लाखों लोग, तो दूसरी तरफ जलालाबाद में दंगे पर काबू पाने तथा अमन-चैन कायम करने की कोशिश।

यात्रा का अंत: इस यात्रा का अंत गुरुद्वारे, कुरबानी और हिंसा तथा हत्याओं की चरम परिणति से होता है। फिल्म के प्रथम भाग में जहां संशय, राजनीतिबाजी और मनुष्य की आदिम जातीय भावनाओं को उकेरा गया है, वहीं दूसरे भाग में घटनाओं से उत्पन्न आतंक, खतरों के बीच जीने की जिजीविषा और निराशा के घटाटोप अंधेरे में आशा की क्षण-क्षण प्रज्ज्वलित होती मरीचिका उभरती है। फिल्म का अंत उस शरणार्थी कैंप से होता है जहां करमो मृतकों की भीड़ में नत्थू की लाश

साक्षात्कार/ **गोविंद निहलाणी**

'तमस' मेरे फिल्मी-जीवन की उत्तम कृति है

माया : क्या कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति प्रतिपादित कराने के लिए यह फिल्म आपसे बनवायी ?

गोविंद : ऐसा तो नहीं है। मुझे तो कहानी अच्छी लगी।

माया : कहीं कुछ परिवर्तन भी करना पड़ा होगा ?

गोविंद : मामूली-सा। पटकथा लिखते समय परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। नाथू (ओम पुरी) का रोल बीच में ही खतम हो जाता था। मैं उसे आखिर तक लेकर गया हूं। मूल कहानी में उसकी मां भी नहीं थी। वह भी जोड़ा गया पात्र है।

माया : इसमें जगह-जगह शांति वार्ताएं पिरोयी गयी हैं और उनमें विवेक से काम लेने की सलाह बार-बार दी गयी है। क्या ये अंश उपन्यास में भी हैं ?

गोविंद : ये पटकथा की जरूरत के मुताबिक रखे गये हैं, मगर उन्हें मूल कथा से परिवर्तित नहीं कहा जा सकता। वही सब तो उस फिल्म को बनाने का उद्देश्य था। अगर वे दृश्य नहीं होते, तो शायद मेरी बात दर्शकों तक पहुंचती ही नहीं।

माया : फिल्म से नाटकीयता को हटाने के प्रयास में कई जगह लगता है कि आपने प्रतिक्रिया तो दिखा दी कि पचासों स्त्रियां कांफिला बना कर जाती हैं और एक कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं, मगर वह दृश्य नहीं दिखाया जिसकी वजह से वे इतनी आतंकित हो चुकी थीं कि आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई भी चारा बचा ही नहीं था।

गोविंद : हां, वह दृश्य जान बूझ कर नहीं रखा। मगर आवाजों और संगीत के माध्यम से वह आतंक पैदा करने की कोशिश जरूर की है। गुरुद्वारे के बाहर जब ग्रंथी और नाथू को सुलहनामे के लिए भेजा जाता है, तो उसकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। वह दृश्य भी मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं वह क्रूरता दिखाये बगैर ही उसका प्रभाव पैदा करना चाहता था।

माया : आपने समस्या को उघाड़ कर दिखाने के लिए शुरू में जो भूमिका बनायी है उसको देख कर शायद दर्शक सोचेंगे कि आपने सरकार की नीति के अनुसार एक खास वर्ग का पक्ष लिया है और दूसरे निरपराधी वर्ग को अपराधी घोषित करने की कोशिश की है। इसे देख कर शायद दर्शक अगले एपीसोड देखने के लिए उत्सुक ही न रहें ?

गोविंद : बस उन्ही लोगों से मुझे कहना है कि जब तक पूरे परिच्छेद न देख लें, तब कोई भी राय कायम न करें। क्योंकि अगर पूर्वाग्रह ने पहले ही घेर लिया, तो वे मेरे फिल्मी-जीवन की उत्तम कृति को देख-समझ ही नहीं पायेंगे। — **महेंद्र सरल**

की तलाश करती है और अंततः उसकी आंखें एक लाश के चेहरे से कफन उठाते ही जड़ रह जाती हैं—इतने बड़े दंगे की शुरुआत का खुद को कारण माननेवाला उसका पति नत्थू अपनी तमाम आत्मग्लानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पा चुका है। फिर वह एक संतान को जन्म देती है—अंधेरे की विदाई के साथ उपजा नयी किरण का प्रकाश। फिल्म का अंतिम दृश्य दर्शकों पर एक साथ कई गहरे वार करता है। गोविंद निहलाणी भी मानते हैं कि यह अंत अगर दर्शको को कुछ हद तक भी झकझोर सके, तो वह अपनी सफलता मानेंगे कि मनुष्य के भीतर की जो जिजीविषा, छल-प्रपंच और कूटनीतिबाजी, अलगाववाद और सांप्रदायिकता, उसे दंगे कराने के लिए प्रेरित करती है, उस पर वह विजय पा सके, क्योंकि आज भी दंगों के वही कारण हैं जो ४८ वर्ष पहले थे—वही 'कुछ' लोगों द्वारा गाय या सूअर कटवा कर एक-दूसरे के पूजा स्थलों के सामने फिकवा देना, फिर सच का पता लगाये बगैर आम आदमी का बौराकर हिंसक बन जाना।

महाकाव्यत्वः 'तमस' सिर्फ एक कथा भर नहीं है—एक बीते हुए हादसे का महाकाव्य है। तमसकार भीष्म साहनी, निर्देशक गोविंद निहलाणी तथा कांग्रेसी नेता बख्शीजी की भूमिका निभाने वाले ए०के० हंगल इस दंगे के चश्मदीद गवाह रह चुके हैं—सैकड़ों-हजारों लोगों को कटते-मरते, महिलाओं को अपहरण-बलात्कार का शिकार होते तथा अपने शहर को लूट-पाट और आगजनी में स्वाहा होते हुए देखा है। उन्होंने इस दर्द को न केवल भोगा है, बल्कि जान बचाकर पलायन भी किया है। इसलिए फिल्म नाटकीय नहीं बनने पायी है।

'तमस' में दो चरित्र और हैं—जरनैल सिंह (वीरेंद्र सक्सेना) तथा एक रेस्तरा में पैगंबर की कहानी सुनानेवाले सईद जाफरी। गोविंद निहलाणी और भीष्म साहनी अपने मन की बात, अपनी खुद की प्रतिक्रिया इन दोनों के माध्यम से न केवल व्यक्त करते हैं, बल्कि उन्हें कथा की मुख्य धारा से जोड़ देते हैं। नेताजी की 'इंडियन नेशनल आर्मी' में रह चुके अनुशासनबद्ध जरनैल सिंह को नेताओं की दोमुंही रणनीति, मौकापरस्ती, कायरता, अनुशासनहीनता तथा दलीय राजनीति में बेहद चिढ है। वह गांधी और नेहरू का सच्चा अनुयायी है, इसलिए घंटाघर पर सही बात जब आम आदमी को बतलाने के लिए खड़ा होता है, तो अज्ञात हाथ उसे शहीद कर देते हैं।

गोविंद ने मूल कथा में कई परिवर्तन भी किये हैं, लेकिन इससे फिल्म में गतिरोध के बजाय स्वाभाविकता का पुट आ गया है। उपन्यास में नत्थू की मां का चित्रण नहीं था, लेकिन फिल्म में वह जितनी देर परदे पर रहती है, सिचुएशंस को जीवंतता प्रदान करती है। इसी तरह उपन्यास में रबाबियों का जिक्र नहीं था, उनके बारे में गोविंद ने अमृतसर के अपने एक निरंकारी दोस्त से सुना और बेहद प्रभावित हुए थे। रबाबी आज भी पाकिस्तान में हैं। उनके गुरु बाला और मरदाना गुरु नानक के शिष्य थे। वे गुरुद्वारों में जाकर शबद-कीर्तन करते थे, लेकिन वे सांप्रदायिक दंगों के दौरान दोनों संप्रदायों के अविश्वास के भाजन बन गये। सिख महिलाओं की कुरबानी का चित्रण भी पंजाब के एक गांव में हुए हूबहू ऐसे ही हादसे के आधार पर किया गया था।

यथार्थ की झलक: 'तमस' की सबसे प्रमुख विशेषता है उसकी गुणवत्ता और उस काल के माहौल को उभारनेवाले मोहल्ले, गलियों, बाजार, घर तथा लोगों के पहनावे और उनकी जबान (भाषा)। फिल्म देखते समय लगता है कि वास्तविक लोकेशन पर जाकर शूटिंग की गयी है, लेकिन सारे दृश्य बंबई में फिल्म सिटी और फिल्मालय स्टूडियों में कला निर्देशक नितीश राय द्वारा तैयार सेटों पर फिल्माये गये हैं। असली पंजाब को सेट पर उतार देने के लिए नितीश राय बधाई के पात्र हैं, उनके सेट 'गांधी' के सेटों की याद दिलाते हैं और स्तर की दृष्टि से वे 'गांधी' के मुकाबले कहीं भी पीछे नहीं हैं। गोविंद निहलाणी 'गांधी' की सेकंड यूनिट के कैमरामैन रह चुके हैं, लेकिन 'तमस' में खुद छायांकन करने के साथ-साथ प्रख्यात कैमरामैन वी०के० मूर्ति का भी सहयोग लिया। छायांकन, सेट और प्रस्तुतिकरण के लिहाज से 'तमस' हालीवुड की किसी भी श्रेष्ठतम फिल्म की तुलना में पीछे नहीं है। ओमपुरी से लेकर एक्स्ट्रानुमा भूमिकाएं करनेवाले कलाकारों तक ने अपने चरित्र को बखूबी निबाहा है—वे कलाकार कम और उपन्यास के जीवंत पात्र ज्यादा लगते हैं। १८ महीने में २०० शिफ्टों में गोविंद ने 'तमस' की शूटिंग की। इसके निर्माण पर लगभग ७५ लाख रुपए खर्च हुए। कम समय में अल्प बजट की फिल्में बनानेवाले गोविंद निहलाणी के लिए यह सारा कुछ काफी तामझाम और बड़े बजट वाली फिल्म भले है—वह ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर इसी फिल्म को रमेश सिप्पी या मनमोहन देसाई अथवा रिचर्ड एटेनबरो ने बनायी होती, तो फिल्म की निर्माण-लागत ५ करोड़ से १५ करोड़ रुपए होती।

उठते सवाल: 'तमस' बहुत सारे सवाल उठाता है। दोनों संप्रदाय के दर्शकों को गोविंद निहलाणी के प्रस्तुतिकरण मे शिकायत भी हो सकती है। रामप्रसाद खत्री नामक एक व्यक्ति के

अनुसार 'मैं हिंदू महासभा की युवा शाखा में १९४६ में भरती हुआ था। हमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि तमाम ऐतिहासिक एवं समसामयिक महापुरुषों की जीवनियां बताकर हममें सच्चरित्रता का भाव पैदा किया जाता था। लेकिन कहीं भी किसी युवक या किशोर को मुर्गी या किसी जानवर को हलाल कर उसमें शूरवीरता नहीं भरी जाती थी। यह सारा प्रसंग ही गलत और कपोलकल्पित है। हिंदू महासभा और आर्य समाज को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।' इसी तरह की प्रतिक्रियाएं बहुत से लोगों ने व्यक्त कीं। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद तथा हिंदू महासभा ने 'तमस' के विरुद्ध आंदोलन भी किया।

दूसरी तरफ बंबई के एक व्यवसायी जावेद सिद्दीकी की 'तमस' का प्रदर्शन रोक देने के लिए दायर की गयी याचिका पर दिये गये अदालत के निर्णय के विरुद्ध 'तमस' के निर्माताओं (फ्रेनी एम वेरियावा तथा ललित एम० बिजलानी) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। २३ जनवरी को 'तमस' प्रदर्शित हो या नहीं, इस पर विचार करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की द्वयखंडपीठ के न्यायमूर्ति बी० लेंटिन तथा सुजाता मनोहर ने २२ जनवरी'८८ को 'तमस' देखी और २३ जनवरी से पुनः 'तमस' के दूरदर्शन पर प्रसारण को जारी रखने की अनुमति दी। न्यायामूर्ति द्वय ने अपने फैसले में कहा, "छहों भाग देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 'तमस' इतिहास के दुखद काल का चित्रण करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह दोनों समुदायों के कट्टरपंथियों और अतिवादियों ने सांप्रदायिक हिंसा शुरू की और किस तरह से दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों और अतिवादियों ने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भोले-भाले लोगों को उल्लू बनाया? किस तरह दोनों समुदायों के कट्टरपंथी और अतिवादी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर तनाव और नफरत फैलाते हैं? आखिर में किस तरह इन सबकी निरर्थकता का लोगों को अहसास होता है और कैसे मानव प्रवृत्ति में निहित सद्भावना उभरती है और दोनों सद्भाव से जीना सीखते हैं।" भाजपा और शिवसेना के अल्टीमेटम के सिलसिले में उन्होंने इतना ही कहा कि "मुझे आशा है बाकी किस्तें देखने के बाद उन्हें इसके पीछे छिपा मंतव्य मालूम होगा—जो सांप्रदायिकता नहीं सद्भाव सिखाता है।" न्यायालय के फैसले का मंतव्य है कि 'तमस' नफरत नहीं सबक सिखाता है। न्यायमूर्ति-द्वय ने कहा भी है कि किस तरह दोनों संप्रदायों के कट्टरपंथी और अतिवादी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक भोलेभाले लड़के को हिंसा का पाठ पढ़ाकर हिंसा करने के लिए उकसाते हैं। सीरियल में यह बात उभारी गयी है कि नफरत-से-नफरत, हिंसा से हिंसा फैलती है और भलाई-से-भलाई और शांति को बढ़ावा मिलता है। इस सीरियल का उद्देश्य है, 'जो हुआ उसे याद रखो, खुद को कट्टरपंथियों और अतिवादियों का मोहरा न बनने दो और अपने विवेक का इस्तेमाल करो।'

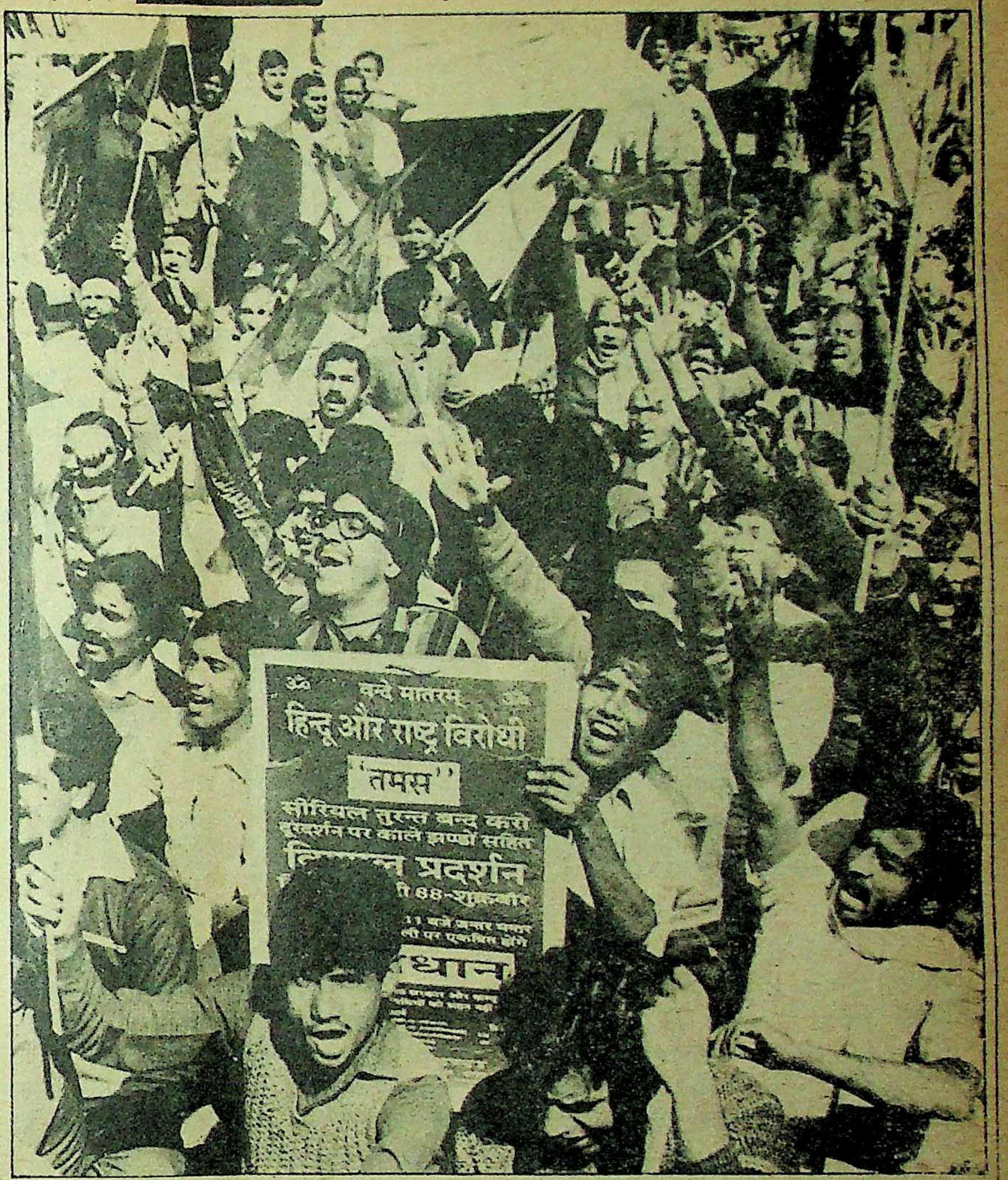

विरोध: २९ जनवरी को दूरदर्शन केंद्र दिल्ली पर भाजपा तथा अन्य हिंदू संगठनों का 'तमस' के विरोध में प्रदर्शन

ऐसा नहीं है कि उस तरह की प्रतिक्रियाओं का आभास गोविंद निहलाणी को नहीं था। 'तमस' के प्रदर्शन में इसीलिए विलंब हुआ, क्योंकि गोविंद किसी भी शर्त पर दूरदर्शन द्वारा 'तमस' में कांट-छांट के लिए तैयार नहीं थे।

नेशनल इंटीग्रिटी कमेटी ने 'तमस' को देखकर जब हरी झंडी दिखला दी, तो दूरदर्शन ने बिना एक भी दृश्य काटे इसके प्रदर्शन की अनुमति दे दी। यों यह मजेदार बात थी कि जब 'तमस' को फिल्म के रूप में बनाने के लिए गोविंद निहलाणी ने फायनेंस के लिए राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम से पेशकश की, तो निगम ने यह कहकर उनकी पेशकश को ठुकरा दिया कि 'अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा!' यह बात दूसरी है कि फिल्म—उद्योग तथा तमाम लोगों के कड़े विरोध के बावजूद इसी निगम ने रिचर्ड एटेनबरो को 'गांधी' के निर्माण के लिए मुंहमांगी धनराशि बिना किसी गारंटी के दे दी थी।

भीष्म साहनी ने उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों के लिए अंग्रेज हुक्मरानों की कूटनीति को दोषी ठहराया था और नत्थू से सूअर कटवाने के प्रकरण को बड़े खुले शब्दों में उकेरा था, लेकिन गोविंद ने इसे उस तरह से नहीं उभारा। दूसरी तरफ हिंदू संप्रदायवाद को उन्होंने जितने खुले ढंग से प्रस्तुत किया, मुस्लिम संप्रदायवाद को सांकेतिकता प्रदान की। पूरी 'तमस' को देखने के बाद लगता है कि हिंदू महासभा और आर्य समाज ने जिस तरह मुसलमानों के विरुद्ध बडे स्तर पर मोर्चाबंदी और लड़ाई की तैयारी की थी, दूसरे पक्ष की तरफ वैसा उस मात्रा में नहीं था।

लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद 'तमस' पिछले दो दशकों में हिंदी में बनी श्रेष्ठतम फिल्म है—तकनीकी गुणवत्ता की दृष्टि से भी और सशक्त प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के नजरिये से भी। इसे देखने के लिए जरूरी है हम अपने चेहरे से सांप्रदायिकता के चश्मे को उतार दें। ■

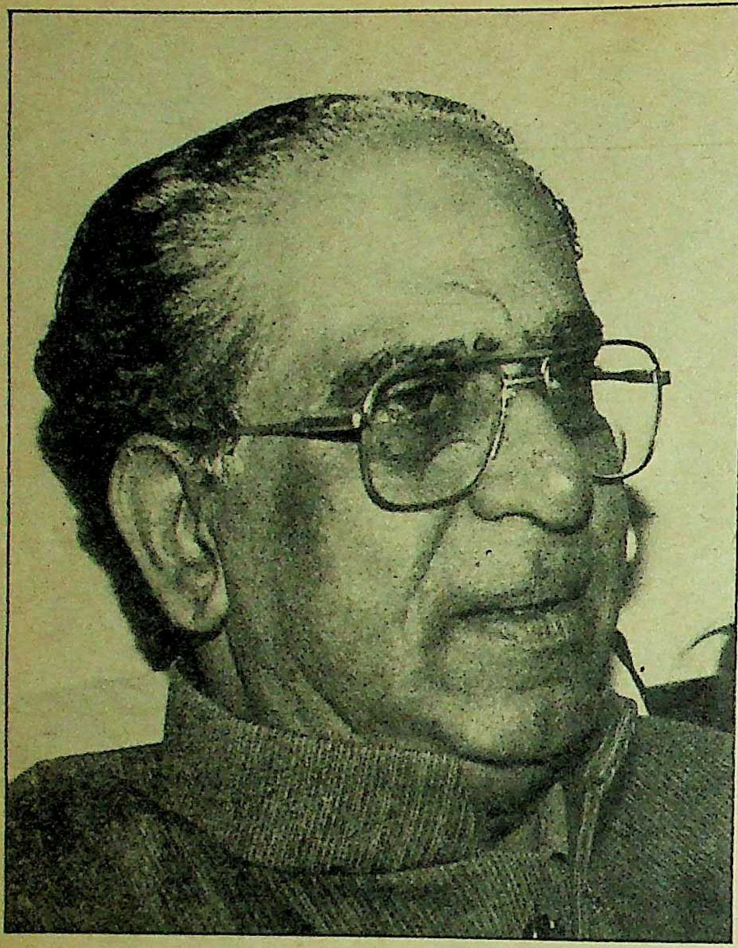

अली सिद्दीकी

वी०पी० सिंह सोचते थे वह भारत के प्रधानमंत्री बन जायेंगे

अली सिद्दीकी वही व्यक्ति हैं जिन पर अमरीकी जासूसी एजेंसी फेयरफैक्स के प्रमुख माइकेल हर्शमैन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 'क्लीन चिट' दिलवाने के लिए उन्हें ६५ लाख रुपए रिश्वत देने की पेशकश की थी। दूसरी बार सिद्दीकी चर्चा का विषय तब बने जब उन्होंने वी०पी० सिंह पर आरोप लगाया कि वह ज़ब वित्तमंत्री थे, तो नार्थ ब्लाक में उन्होंने हर्शमैन से दो बार मुलाकात की थी और बोफोर्स-कांड में प्रधानमंत्री या उनके परिवार के किसी सदस्य के शामिल होने की संभावना के बारे में खोजबीन करने को कहा था। सिद्दीकी ने यह दावा किया था कि २५ अगस्त '८७ को हर्शमैन ने एक मुलाकात में उक्त जानकारी दी थी। वी०पी० सिंह इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा है कि समय आने पर वह इसके सबूत भी पेश करेंगे।

सिद्दीकी इसके पहले भी कई विवादों के केंद्र में रह चुके हैं। उनके गृह नगर हैदराबाद के सांसद जयपाल रेड्डी तीस साल पहले उनके द्वारा निकाली जा रही उर्दू पत्रिका 'इब्नुल वक्त' पर आक्षेप करते हुए कहते हैं, "पत्रिका का उद्देश्य केवल लोगों में दबदबा बनाना था।" साठ के दशक में जारी तेलंगाना आंदोलन के समय उन्होंने मुस्लिम कट्टरवाद को उभारने की कोशिश भी की थी। १९६९ में जब उन्हें अखबारों ने सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का दोषी करार दिया, तो उन्होंने पाला बदला और राष्ट्रीय एकता की बातें करने लगे। इसी तरह वह पहले मुख्यमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी की तरफ से एम० चेन्ना रेड्डी की खिलाफत करते रहे, किंतु जब ब्रह्मानंद ने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वह उनकी खिलाफत में जुट गये। इस सबके बाद उन्होंने नरसिंह राव को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान छेड़ा और यहीं से उन्हें दिल्ली दरबार में घुसपैठ करने का मौका मिला। १९७१ में उन्होंने दिल्ली में रैलियां वगैरह आयोजित कीं जिससे वह मोहम्मद यूनुस और उनके पुत्र आदिल शहरयार के संपर्क में आये और यहीं से गांधी परिवार से भी घनिष्ठता बढ़ी। इन संबंधों का सिद्दीकी ने भरपूर फायदा उठाया और प्रदेश के व्यापारियों का दिल्ली का काम कराने लगे।

आपातकाल के दौरान सिद्दीकी ने अपना धंधा बदल दिया। उन्होंने युवकों को खाड़ी के देशों में काम दिलाने के लिए 'अल जम जम' चयन एजेंसी' खोल ली। १९७८ में इस एजेंसी को उन्होंने ट्रेवेल एजेंसी में तब्दील कर दिया।

सिद्दीकी पर चयन एजेंसी से संबंधित कई आरोप हैं। कहा जाता है कि 'पंजीकरण फार्म' के नाम पर उन्होंने लगभग २० लाख रुपए बटोरे। जयपाल रेड्डी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने लगभग १०० युवकों से दस-दस हजार रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर वसूले थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इनमें से कई ने पुलिस में रपट भी लिखायी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के तहत कुल मिलाकर दस मामले उनके खिलाफ दर्ज कराये गये थे। पुलिस रिकार्ड के अनुसार २०० के आसपास उनकी इस चालबाजी के शिकार हुए थे। जयपाल रेड्डी के अनुसार, "पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली का फोन आया और सिद्दीकी का बाल बांका न हो सका।" लेकिन एन०टी० रामाराव के मुख्यमंत्री बनते ही ३० नवंबर, १९८३ को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयपाल रेड्डी का कहना है, "शिकायत करने वालों को धमका दिया गया, जिससे मामला कमजोर हो गया और वह साफ बच निकले।"

मोहम्मद यूनुस के पुत्र आदिल शहरयार को जब अमरीका में धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया, तो सिद्दीकी का नाम एक बार फिर उछला था। इस समय सिद्दीकी राजीव गांधी के रक्षक के रूप में चर्चित हो रहे हैं। फेयरफैक्स मामले में उनकी भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रस्तुत हैं 'माया' के साथ उनकी बातचीत के प्रमुख अंश:

क्या आपने राजीव का नाम अलग रखने के लिए हर्शमैन को रिश्वत दी ?

वकील (फिलिप्स) वोलेन ने हर्शमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हर्शमैन ने इसके जवाब में अदालत में,जो बयान दिया है, उसमें मेरा नाम कहीं नहीं है। वोलेन ने यह मुकदमा इसलिए चलाया, क्योंकि हर्शमैन ने इलजाम लगाया था कि टेलीफोन के जरिए उसको रिश्दत देने की कोशिश की गयी। क्या उसको किसी ने मेरे नाम का जिक्र करने से रोका था ? फिर मैं हर्शमैन से अकेले होटल में मिला था। वह कह सकता था कि उस मुलाकात में मैंने उसे रिश्वत की पेशकश की थी। इस तरह कहानी फिर अलग होती, जिसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता।

फेयरफैक्स की नियुक्ति पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

अगर कुछ लोगों ने रिलायंस से पैसा खाया है, तो ऐसे लोग बहुत हैं। रिलायंस एक निजी कंपनी है। (मामला मुल्क से संबंधित है)। कुछ लोग पैसा बना रहे हैं। कौन लोग पैसा बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हम खुद बुरे हैं। उद्योगपतियों ने यह देश बनाया है, उद्योग-धंधे कायम किये, हजारों को रोजगार दिये। उनको हथकड़ियां पहनाकर, अदालत में ले जाकर उनकी बेइज्जती का हक आपको नहीं है। वी०पी० सिंह सोचते थे कि वह भारत के प्रधानमंत्री बन जायेंगे और हर्शमैन समझता था कि वह भारत का अटार्नी हो जायेगा। यह मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। यह वी०पी० सिंह की अगुवाई में राजीव सरकार का तख्ता पलटने और कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश थी। यह गलत है कि राजनीति में आप बाहरी मुल्कों के साथ साजिश रचें। अगर हिम्मत है, तो वोट हासिल करके ऐसा करें।

आप वी०पी० सिंह के खिलाफ क्यों हैं ? :

वह मेरे दोस्त हैं। मैंने सन आफ इंडिया में उनके फोटो छापे हैं, लेकिन मुझे दुख है कि उनकी करतूतों से देश का नाम बदनाम हुआ है। जब वह वित्तमंत्री थे, तो रिलायंस का तूफान खड़ा किया और जब रक्षामंत्री थे, तो बोफोर्स का। अगर उन्हें रक्षा मामले में भ्रष्टाचार का मामला दिखायी पड़ा था, तो वह सेना के गुप्तचर विभाग को उसे सौंप सकते थे। सीबीआई या रा को मामला नहीं सौंपना चाहते थे, तो क्या सैन्य गुप्तचर जांच आयोग नहीं बैठा सकते थे ? वह महज इसके पीछे पडे रहे कि पैसा किसने खाया है। इसके लिए उन्होंने दुनिया को बताया कि हम खराब हथियार खरीद रहे हैं। उन्होंने सीआईए की मदद की है और इसी आधार पर पाकिस्तान को अमरीकी मदद मिली। वी०पी० सिंह ने डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे की जांच का हुक्म दिया, जिसे पश्चिमी जर्मनी से खरीदा गया था और पश्चिमी जर्मनी अमरीका का मित्र देश है।

क्या रक्षा सौदों की जांच के आदेश नहीं दिये जाने चाहिए थे ? :

मेरा मतलब यह नहीं है। इस मुल्क को लूटने वाले हैं, बनाने वाले हैं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसका घर खोद रहे हैं, ये जातीय मामले हैं। मुझे गहरा दुख है कि हिन्दुस्तान की नाक कट गयी। हम १९४७ से हथियार खरीद रहे हैं, पर क्या कुछ उजागर हुआ ? एक जांच कमेटी बैठायें, अफसरों को बर्खास्त कर दें। इसमें फौजी अफसर भी होंगे, जिन्होंने हथियारों को चुना होगा। इसके लिए महज रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। (रिश्वत के लिए) जब तक वी०पी० सिंह रक्षामंत्री नहीं बने और सार्वजनिक जांच का हुक्म नहीं दिया, तब तक बोफोर्स कांड नही उभरा था।

रिलायंस के बारे में आपकी क्या राय है ?

हालात ऐसे थे कि हर्शमैन रिलायंस के पीछे पड़ा था, इसलिए मेरे द्वारा उसका नाम इस्तेमाल करना लाजिमी था। मुझे उस मंजिल तक पहुंचना था और हालातों का जायजा लेना था। मुझे उसको और उसका ठिकाना देखना था। मैंने सब कागजात हासिल कर लिये, जो उसके पास थे। दरअसल, लतीफ खां (आप्रवासी भारतीय) ने जो मुकदमा दायर किया था, उसका आधार मेरे द्वारा दिया गया हर्शमैन का ब्रोशर (दलाल, अढ़तिया) था।

हर्शमैन के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

मैंने उसका पूरा कच्चा-चिट्ठा मालूम किया। वह किस अस्पताल में पैदा हुआ, उसका क्या नाम है, किसकी संतान ? सब कुछ। उसके चार नाम हैं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसकी पहली पत्नी की हत्या हो गयी थी और मामला अभी भी एफ०बी०आई० (अमरीकी गुप्तचर एजेंसी) के हाथ में है। अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है जो उसकी सेक्रेट्री भी है। उसके पास लाइसेंस नहीं है। वह महज एक सीआईए एजेंट है। अब वह समझौता करना चाहता है। सारे वकील वोलेन के खिलाफ लगाये उसके इलजामों के कारण उसके खिलाफ हो गये हैं। जिन दो वकीलों को उसने तैनात किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसे वकील तक नहीं मिल रहे हैं। दरअसल, रिश्वत देने वाला खुद हर्शमैन था।

जयपाल रेड्डी

जयपाल रेड्डी के अनुसार, "पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली का फोन आया और सिद्दीकी का बाल बांका न हो सका।" लेकिन एन०टी० रामाराव के मुख्यमंत्री बनते ही ३० नवंबर, १९८३ को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयपाल रेड्डी का कहना है, "शिकायत करने वालों को धमका दिया गया, जिससे मामला कमजोर हो गया और वह साफ बच निकले।"

हर्शमैन रिश्वत क्यों देगा ? :

वी०पी० सिंह ने उसे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में ३४ लोगों की एक सूची दी जिसमें तमाम नामीगिरामी लोगों के नाम थे। हर्शमैन उस सूची के एवज में रिश्वत चाहता था। पहले सूची में सबसे ऊपर अरुण नेहरू का नाम था, जिसे बाद में दिल्ली (वी०पी० सिंह) की हिदायत पर हटा दिया गया। हर्शमैन ने यह खुद मुझे बताया था। अरुण नेहरू के नियंत्रण में तमाम मारुति एजेंसियां थीं और यह बात जगजाहिर है। मेरे पास सबूत हैं कि हरेक एजेंसी से ८ से २० लाख रुपए वसूल किये गये। इस पर जांच आयोग बैठाये जानें पर, इस शर्त पर कि काला धन देने वालों को माफ कर दिया जायेगा, मैं तमाम सबूत पेश कर दूंगा।

अपने खिलाफ फौजदारी के मामलों पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

मेरे बीसियों लोगों के साथ मुकदमे चले हैं, पर एक में भी सजा या जुर्माना हुआ तो कहिये। मैं आपके खिलाफ १० दरख्वास्तें अभी भेज सकता हूं। उसके बाद फौरी कार्रवाई शुरू हो जायेगी। रिक्शाचालक मोहम्मद अली का मामला लें जिसने शिकायत की थी कि मैं २ हजार रुपए लेकर फरार हो गया। इस रकम से तो हैदराबाद से दिल्ली का मेरा हवाई जहाज का किराया भी पूरा नहीं पड़ता। उस आदमी ने अदालत में मुझे पहचानने से इनकार किया। मेरे पास तो उसका यह हलफनामा है कि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा।

आप मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हैं। चलो मैंने बोल दिया कि मैं वाल्मीकि (जो सिद्दकी के अनुसार सैकड़ों महिलाओं की हत्या करते थे) का दादा हू। आप क्या कर लेंगे ? मेरे ऊपर ४२० के कई केस हैं, जो मारपीट, डकैती या दूसरे अपराधों से संबंधित नहीं हैं, किंतु वी०पी० सिंह पर तो देश के खजाने को लूटने, गद्दारी करने के इलजाम हैं। उन्होंने तमाम सूचनाएं बाहरी देशों को दी हैं।

मोहम्मद यूनुस और राजीव गांधी से संबंधों पर कोई टिप्पणी ?

इन दोनों परिवारों से करीबी रिश्ते की वजह से ही मुझ पर हमले किये जा रहे हैं। यूनुस से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मरते दम तक इंदिरा गांधी का समर्थक रहूंगा। उन्होंने मुझ जैसी मामूली हस्ती वाले को अपनाकर नयी जिंदगी बख्शी है। मेरे खिलाफ इलजाम लगाये जाने पर वह अकसर कहा करतीं, "इस तरफ तवज्जो मत दो। मैं जानती हूं तुम ठीक हो।" इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में जमीन- आसमान का फर्क है, मगर मुझे तो इस खानदान से प्यार है।

—अभय अग्रवाल

जय दुबाशी का

वित्तमंत्री को खुला पत्र

प्रिय वित्तमंत्रीजी,

आप आगामी बजट सत्र के कारण संभवत: काफी व्यस्त होंगे। बजट का समय वैसे भी चिट्ठी-पत्री का समय होता है, जिसमें चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष से लेकर उपभोक्ता संघों के सचिवगण तक इसमें रत, रहते हैं। पता नहीं जो पत्र आपको लिखे गये हैं, उन्हें आपने पढ़ा भी है या नहीं अथवा यदि पढ़े बिना फाइल कर दिया है, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? निस्संदेह यह आम पत्रों की तरह होंगे, जिनमें आयकर की वर्तमान सीमा को, वह चाहे जो भी हो, बढ़ाकर २५००० रुपए करने जैसे सुझाव होंगे। आप पूछेंगे कि २५००० रुपए ही क्यों, लागत भत्ता पुन: शुरू करने और लाभांश पर कर समाप्त करने का अनुरोध किया गया होगा। और हां, किसी ने आपको काला धन और स्विस बैंकों में जमा धन बरामद करने के बारे में भी जरूर लिखा होगा।

यदि मैं आपकी जगह होता, तो इन तमाम सुझावों पर कोई ध्यान न देता। आयकर की सीमा न बढ़ाने से आस्मान सिर पर गिरने वाला नहीं है। यदि आप निजी आयकर को भी पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, तो भी रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां तक अन्य सुझावों का संबंध है—मसलन पूंजीगत कर आदि—उस पर भी यही बात लागू होती है। भारत में आयकरदाताओं की संख्या इतनी नगण्य है कि यह सोचना भी हास्यास्पद है कि कुछ करोड़ रुपए इधर-उधर करने से आपके राजस्व अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका राजस्व बढ़ ही सकता है और रिजर्व बैंक भी रुपयों से ठसाठस भरा हो, सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अर्थव्यवस्था फलफूल रही है। अपने पूर्वाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह का १९८५ का बजट याद कीजिए। उस वर्ष शेयर बाजारों की पौबारह थी और सैकड़ों शेयर दलालों ने खूब चांदी काटी। असंख्य नये उद्योग रातोरात खुल गये और नये 'इशू' (धन-संग्रह के लिए शेयर, ऋण-पत्र आदि) दस से बीस गुना और कुछ तो सौ गुना तक 'ओवर सब्सक्राइब्ड' (अतिरिक्त मांग) हुए। किंतु आज वे उद्योग कहा हैं और कहां है, शेयर बाजार? अधिक समय न सही, तो गत एक वर्ष से शेयर बाजार मंदी का बुरी तरह शिकार है। भले ही आप असंख्य समितियां गठित क्यों न करें या शेयर बाजार के प्रमुखजन दिल्ली के दौरे करें—यह मंदी बरकरार रहेगी। और कहां हैं, आकाश के तारे तोड़ कर लाने का वायदा करने वाली कंपनिया जो चार पैसे का मुनाफा भी नहीं क़मा-दिखा सकीं? और कहां हैं, खुद विश्वनाथ प्रताप सिह जो अर्थव्यवस्था में क्रांति करने और गाड़ी को पटरी पर लाने वाले थे, किंतु जो एक दूसरे प्रकार की क्रांति की खोज में अब सुलतानपुर और सिंहभूमि की धूलभरी सड़कें नाप रहे हैं?

सवाल यह नहीं कि आप अर्थव्यवस्था से क्या लेते हैं, सवाल है कितना कुछ लेते हैं। महत्व इसका है कि आपका बजट संतुलित है या नहीं। किंतु इससे भी अधिक महत्व इसका है कि लोगों की जेबों से जो धन आप लेते हैं, उसका क्या करते हैं। कुछ भी हो, यह आपका धन नहीं, क्योंकि सरकार कोई कमाई नही करती और तथाकथित सार्वजनिक संस्थानों को भी फायदा नहीं होता। इसलिए जब आप अपना हिस्सा लें, तो आपके दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका किस काम में उपयोग आप करेंगे। बाकी बातें गौण और संभवत: अप्रासंगिक हैं।

कृपया आप अपने अधिकारियों को वह तालिका देने को कहें, जिसमें दिखाया गया है कि सरकार अभी तक, गत तीस वर्षों में, कितना धन लोगों की जेबों से लेती रहती है। आपको आंकड़े देखकर ताज्जुब होगा। आपकी सरकार—और जितनी आपकी है, उतनी ही मेरी भी है, भले ही वह कागज पर हो—सामान्यत: छठे और सातवें दशक के प्रत्येक अच्छे और बुरे वर्ष में करों के रूप में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लगभग २७ प्रतिशत हथियाती रही है। १९७५-७६ के वर्ष में, जब आप उ० प्र० के मुख्यमंत्री थे, सरकार ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ८० प्रतिशत भाग तक हजम कर लिया था। यह अनुपात वित्तमंत्रियों की क्षुधा, उनके अथवा उनके सलाहकारों के अज्ञान से घटता-बढ़ता रहा है, किंतु पहली बार १९६५-६६ में यह ५० प्रतिशत की सीमा पार कर गया था। यह १९६६ के रुपए के अवमूल्यन के प्रख्यात वर्ष के एक साल पहले की बात है तथा कइयों के अनुसार इसी वर्ष से वास्तविक क्षय की दागबेल बढ़ी। और हमारी विकास दर उन वर्षों मे क्या थी—एकमुश्त ३.५ प्रतिशत वार्षिक की। यह सिलसिला वर्षों जारी रहा, भले ही बजट मुनाफे का हो या घाटे का, मौसम अच्छा हो या बुरा।

अब आठवे दशक में प्रवेश करें। इस दौरान अनुपात प्रशंसनीय रूप में नीचे आया। सात वर्षों—१९८०-८१ से जो श्रीमती गांधी का जनता शासन के बाद सत्ता में वापसी का पहला वर्ष था, १९८६-८७ तक इस अनुपात का औसत लगभग २२ प्रतिशत था। आप कह सकते हैं कि यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। किंतु यह स्मरण कीजिए कि सरकार की कर के रूप में वसूली गयी राशि का अनुपात कमोबेश जैसा-का-तैसा बरकरार रहा, गोकि एक या दो वर्ष ऐसे भी रहे हैं, जब यह लगभग ३० प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसका अर्थ यह है कि राज्य की क्षुधा इस दौरान ऐसी उग्र नहीं थी, जैसी पहले हुआ करती थी और यही उदारीकरण का अर्थ है। उसका नतीजा जगजाहिर है। विकास दर बढ़कर अब औसत ४.८ प्रतिशत हो गयी है। पहले कई वर्षों तक यह ३.५ प्रतिशत बनी हुई थी। इस प्रकार इस तथ्य के बावजूद कि पहले जैसी अब भरपूर कृषि पैदावार नहीं रह गयी है, विकास दर में एक तिहाई बढ़ोतरी हुई है।

यदि मैं आपकी जगह होता, तो कोशिश करता कि यह अनुपात अगले कुछ सालों में गिरकर २० प्रतिशत पर पहुंच जाये और शताब्दी के अंत तक यह अनुपात कायम रहे। मैंने २० प्रतिशत का उल्लेख किया है, क्योंकि कोलिन क्लार्क जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राज्य जब इस अनुपात से अधिक आयकर की वसूली का प्रयास करता है, तब समाज उसका प्रतिरोध करता है। पहले तो लोग कर-अदायगी में टालमटोल करते हैं और फिर अपनी आर्थिक गतिविधियों में टालमटोल करते हैं। लोग सवाल करते हैं कि जब सरकार उनकी कमाई का बड़ा भाग छीन लेती है, तो वे कारोबार क्यों करें? इस प्रकार वे कमाई करना बंद कर देते हैं अथवा कर अदा करना बंद कर देते हैं, जिसका फल, जहां तक आपके राजस्व का संबध है, समान होता है।

१९८७-८८ का वर्ष एक बुरा वर्ष रहा है, जिसमें एक या दो प्रतिशत से अधिक के विकास की संभावना नहीं तथा कीमतें दो अंकों के स्तर पर पहुंच गयी हैं। पिछले वर्ष सरकार

केन्द्र सरकार इस समय
१५० करोड़ रु० एक दिन में खर्च करती है।
इसका अर्थ है ६ करोड़ फी घंटा
या एक करोड़ प्रति १० मिनट में और
क्या आपको एक औसत भारतीय
गांव की आय का पता है?
यह लगभग १६ लाख रु० सालाना है।
इसका मतलब है कि आपकी सरकार प्रति घंटा
जितना रुपए खर्चा करती है उतना ४० गांव
मिलकर पूरे एक साल में कमाते हैं।

ने राष्ट्रीय आय के जिस भाग का उपयोग किया, उसकी दर १७ प्रतिशत थी। इसे इसी स्तर पर बना रहने दीजिए। आपने पहले ही इस्पात और कोयले के दाम बढ़ा दिये और प्रति लीटर पेट्रोल में एक रु० से अधिक की मूल्यवृद्धि कर इसे इतना महंगा बना दिया, जितना दुनिया में कहीं और नहीं है। दरअसल हमारा इस्पात भी दुनिया में सबसे महंगा है। अनुमान है कि बजट पूर्व की इन वृद्धियों से, जो एक प्रकार के कर ही हैं, आपको पूरे वर्ष में लगभग २४०० करोड़ रु० मिलेगा। आय-वृद्धि इस वर्ष धन के रूप में १२००० करोड़ रु० से अधिक नहीं होगी, जिसका मतलब है कि आपको अतिरिक्त करों का अपना २० प्रतिशत भाग पहले ही मिल चुका है। इसलिए पहली बात यह याद रखनी चाहिए कि करों को यदि घटाया नहीं जाये, तो उसे ज्यों-का-त्यों बने रहने देना चाहिए। व्यक्तिगत आय सीमा को बढ़ाकर या अप्रत्यक्ष करों—जैसे तटकर शुल्कों,आबकारी आदि—को घटाकर पहली सलाह पर अमल किया जा सकता है।

किंतु वित्तमंत्री मात्र करों तक सीमित नहीं। बजट हिसाब-किताब के साथ-साथ एक आर्थिक कवायद भी है और इसी समय पहले पहलू पर कुछ ध्यान दिया गया। मसलन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर आप पायेंगे कि गत दस वर्षों में आपकी सरकार अपने स्वयं के साधनों से काम चलाने में समर्थ नहीं रही और घरेलू खर्चों के प्रबंध के लिए उसे अपनी जमा-पूंजी निकालनी पड़ी है। यह वैसा ही है, जैसे मुझे मकान का किराया देने के लिए ओवर ड्राफ्ट लेना पड़े। यह बड़ी बुरी बात है कि कोई सरकार दुनिया की निर्धनतम जनता से इस वायदे पर धन वसूले कि उसे विकास के लिए खर्च किया जायेगा और आमदनी होगी और फिर उसे अपने ऊपर खर्च करे। क्या हर रुपए का, जो सरकार खर्च कर रही है, सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या सरकार जरूरी कामों में हरेक रुपया खर्च कर रही है? केन्द्र सरकार इस समय १५० करोड़ रु० एक दिन में खर्च करती है। इसका अर्थ है ६ करोड़ फी घंटा या एक करोड़ प्रति १० मिनट में। और क्या आपको एक औसत भारतीय गांव की आय का पता है? यह लगभग १६ लाख रु० सालाना है। इसका मतलब है कि आपकी सरकार प्रति घंटा जितना रुपया खर्च करती है, उतना ४० गांव मिलाकर पूरे एक साल में कमाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, ये दुनिया के निर्धनतम गांव हैं। ऐसी सूरत में हमें उनका धन अंधाधुंध खर्च करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।

अब मैं दो को छोड़, तीसरे सुझाव पर आता हूं। सबसे ज्यादा अनापशनाप खर्च करने वाले सरकारी (सार्वजनिक) संस्थान हैं जो साधनों को मुहैया करने की जगह उन्हें चट कर जाते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है। आप उद्योगमंत्री रह चुके हैं और आपको जानकारी है कि ये इकाइयां कैसे काम करती हैं। इनमें से एक दर्जन के लगभग तो संतोषजनक रूप से काम करने वाली कहो जा सकती हैं, शेष देश के साधनों और कोष के लिए एक भारी बोझ हैं। इन सरकारी इकाइयों को प्रति वर्ष होने वाले भारी घाटे की भरपाई के लिए मूल्यवृद्धि की जाती है, जिसका निशाना करदाताओं को बनना पड़ता है। चार साल पहले भारतीय इस्पात प्राधिकरण को रोजाना एक करोड़ रु० का घाटा होता था। यह घाटा तब खतम हुआ, जब इस्पात की कीमतें बढ़ा दी गयीं और कंपनी को मुनाफा-यदि इसे आप सचमुच मानें—होने लगा। कंपनी दुबारा अपने पुराने ढर्रे पर आ गयी है। एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार हाल की मूल्यवृद्धि के बावजूद कंपनी को इस वर्ष ३५० करोड़ रु० का घाटा होने की संभावना है, जो रोजाना करीब एक करोड़ रु० के बराबर है। आप तब तक अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, जब तक हमारी ७५००० करोड़ रु० की पूंजी से बनी ये सरकारी इकाइयां, अन्य जिंसें तो दरकिनार, सस्ता इस्पात और कोयला तक मुहैया नहीं करतीं?

अवश्य ही आप अपने बजट भाषण में वही बाते कहेंगे, जो इन तमाम वर्षों में हर वित्तमंत्री कहता आ रहा है। मसलन यह बात कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का हमारी सशक्त अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है और उन्हें सक्षमतापूर्वक काम करना चाहिए। किंतु वह ऐसा कर नहीं पाती और हर वर्ष उनका किसी-न-किसी रूप में उद्धार किया जाता है। आपके पूर्वाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर एक श्वेतपत्र जारी करने का जो वायदा किया था, वह कागजी साबित हुआ हैं। आप दृढ़ रवैया अपनायें और हमें बतायें कि हालात दुरुस्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? क्या आप इन कंपनियों को बेचना चाहेंगे—यह सोचकर कि इनके खरीदार हैं—गोकि वैसे इन सफेद हाथी जैसी कंपनियों के शेयर भला कौन खरीदना चाहेगा? अथवा आप इन्हें बंद कर देंगे? यही काम श्रीमती थैचर ने इंग्लैंड में किया। आप देखें इसका ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? वह अब यूरोप की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है गोकि व्यापक पैमाने पर हुई बेरोजगारी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।

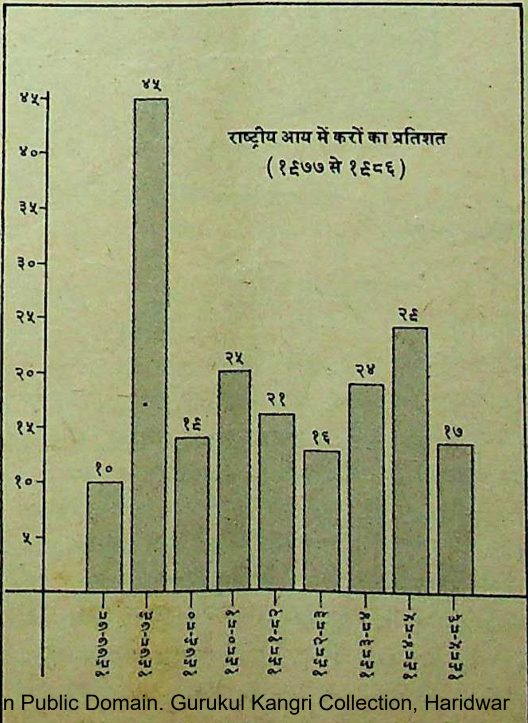

यदि आप पैसे पर ध्यान देंगे, तो रुपया खुद अपना ध्यान रखेगा। मैंने आपको पैसा बचाने के कम-से-कम तीन तरीके बताये हैं—अतिरिक्त सरकारी खर्चे को वार्षिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के पांचवें भाग से कम रखें, राजस्व खर्चों में कमी जिससे राजस्व हिसाब-किताब में घाटा न हो जैसा कि अभी है और सार्वजनिक क्षेत्र को कूच के आदेश जो देश की सबसे मोटी 'पवित्र गाय' है। यदि आप इनमें से एक पर भी अमल शुरू करेंगे, तो हम प्रगति के सही पथ पर अग्रसर होंगे। हमें भी अपने प्रेस्ट्राइका (उदार दृष्टिकोण के लिए रूसी शब्द) की आवश्यकता है, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में, क्योंकि दोनों देशों के सामने समान संकट है, जिसे मैं 'बड़ी सरकार के संकट' का नाम दूंगा। यह अवश्य है कि हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें एक विशाल विकसित निजी क्षेत्र है और इसी दिशा में सोवियत संघ अपनी क्रांति के ७० वर्षों के बाद धीरे-धीरे अग्रसर होने को प्रयासरत है। किंतु अर्थव्यवस्था में मूलभूत तब्दीली के बिना—और यही 'प्रेस्ट्राइका' का अर्थ है— मात्र कर दरों की बंसी बजाना व्यर्थ होगा। आप रूसियों से भी बदतर हालत में हैं, क्योंकि उनकी आबादी हमसे एक तिहाई है और उनका भूभाग हमसे काफी बड़ा है। हमें फूंक-फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि पेट भरना है अनगिनत लोगों का और साधन हैं गिनती के।

अंतिम बात की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट केवल हिसाब-किताब और आर्थिक कसरत ही नहीं, यह एक राजनीतिक कार्रवाई भी है। यदि आप और आपकी सरकार आवश्यक राजनीतिक संकल्प शक्ति का परिचय जैसा गोर्बाचेव और थैचर ने दिया, स्थिति को सुधारने के लिए नहीं दिया, तो आपकी सांख्यिकी (जोड़-घटाने की) कवायद नाकाम रहेगी। किंतु यदि आपकी बुनियादें मजबूत हैं और वहीं से आप श्रीगणेश करते हैं, तो आपकी कुछ सार्थक उपलब्धि संभव है।

आपका विश्वसनीय
जय दुबाशी

किसी को चिंता नहीं है पंजाब की ?

पंजाब की हालत अत्यंत नाजुक हो गयी है। हर दिन दसियों लोग आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो रहे हैं, मगर रिबेरो की पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। केवल जनवरी में ही २०० से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिये गये। कानून और व्यवस्था के बारे में जो दावे किये जा रहे थे वे सब झूठे निकले। इस सबसे ज्यादा दुखद पक्ष यह है कि समस्या को सुलझाने की कोई ईमानदार कोशिश न तो केंद्र कर रहा है और न ही अकाली नेता। सभी इस 'आग' में अपनी-अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश में हैं। तो क्या यह मान लिया जाये कि पंजाब अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से उसका शांति की ओर लौटना लगभग असंभव हो गया है? पेश है,बदलते हालात पर एक ताजातरीन रपट:

समाधान केंद्र के हाथ में है: दर्शन सिंह रागी

पंजाब-समझौता बेकार गया: बरनाला

पंजाब में उग्रवादियों से राजनीतिज्ञों तक और पुलिस से लेकर आम आदमी तक हर किसी के पास पंजाब में हो रहे खूनखराबे के संबंध में अपना विश्लेषण है, अपनी व्याख्या है। भिंडरवाले, उसकी गिरफ्तारी और फिर ब्लू स्टार आपरेशन में उसकी मौत आदि को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन व्यथा यही है कि किसी के पास कोई समाधान नहीं है। पक्के आशावादियों को भी यह विश्वास नहीं है कि समस्या का समाधान होगा और शांति बहाल हो जायेगी। 'माया' द्वारा लिये गये प्रकाश सिंह बादल, दर्शन सिंह रागी और अकाली दल के नेता बलवंत सिंह के साक्षात्कारों के बाद भी यही बात सामने आयी। इन नेताओं से बातचीत करने पर पंजाब में जारी रक्तपात के थमने के कोई आसार नहीं दिखे। इन नेताओं के अव्यावहारिक रवैये से यह भय उत्पन्न होता है कि पंजाब में बंदूकों के मुंह अभी बंद नहीं होंगे, कम-से-कम मौजूदा संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत तो बिलकुल नहीं। सिख नेता ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि वह पंजाबी जनता और उग्रवादियों के करीब आयें जिससे केंद्र उनके साथ बातचीत शुरू कर सके। पंजाब में हो रहे खूनखराबे में केंद्र की भूमिका भी कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसके नेक इरादों से पंजाब नरक बना। अलगाववादी [illegible]

साक्षात्कार/प्रकाश सिंह बादल

मेरे द्वारा सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता

गुरचरण सिंह तोहड़ा के अलावा प्रकाश सिंह बादल अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्हें केंद्र कभी अपने विश्वास में नहीं ले सका। लंबे समय तक हिरासत में रहने के बाद हाल में जब उन्हें छोड़ा गया, तो आशा की किरण नजर आयी थी कि उग्रवाद को खतम करने में वह मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत शुरू करने के लिए उन्होंने पांच कठिन शर्तें केंद्र के सामने रख दी हैं।

बादल ने पंजाब समझौते को कभी पसंद नहीं किया था। वह इसे अव्यावहारिक और सिखों के साथ धोखा मानते हैं। केंद्र पर तो वह बुरी तरह खफा हैं। पंजाब समस्या के लिए वह नेहरू वंश के तीनों प्रधानमंत्रियों को दोषी मानते हैं। उनके अनुसार उन्होंने हमेशा वादाखिलाफी की और धोखा दिया। पंजाब समस्या के समाधान के लिए यह राजनीतिक हल के पक्षधर हैं और मानते हैं कि केंद्र ही इसका निपटारा कर सकता है। प्रस्तुत हैं, उनकी 'माया' के साथ हुई विभिन्न मुद्दों पर बेबाक बातचीत के प्रमुख अंश:

माया: आपके खयाल में पंजाब की स्थिति के बिगड़ने के कौन से कारण हैं?

बादल: आजादी के बाद से केंद्र ने जो बड़ी गलतियां की हैं, वही पंजाब के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार हैं। नेहरू वंश के तीनों प्रधानमंत्रियों ने हमें धोखा दिया। नेहरू ने आजादी के पहले सिखों से जो वादे किये थे, वे उन्होंने पूरे नहीं किये। श्रीमती गांधी ने हमें छोटा-सा पंजाबी सूबा और रावी-ब्यास के पानी का कम हिस्सा दिया। राजीव गांधी ने पंजाब समझौते को लागू नहीं किया। निर्दोष लोगों और धार्मिक नेताओं को जेल में ठूंस दिया है। कथित बागी फौजियों को भी छोड़ा नहीं गया है। जाली मुठभेड़ें हो रही हैं। यही सब कारण हैं, जिन्होंने पंजाब को आज की भयावह स्थिति में ला दिया।

माया: आप दो मर्तबा पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस समय ये प्रश्न आपने केंद्र के सामने क्यों नहीं रखे थे?

बादल: आप 'मीडिया' के लोग मेरे पास नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आते हैं। जब १९७१ में मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने पानी के बंटवारे का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी, तो दरबारा सिंह ने केस वापस ले लिया

माया: मौजूदा हालात के लिए आप किन्हें दोषी मानते हैं—धर्म को, आर्थिक असमानता को, कानून और व्यवस्था को या फिर इन सभी को?

बादल: कानून और व्यवस्था का मामला तो हरगिज नहीं है। यदि यह बात होती, तो रिबेरो अब तक इस समस्या को निपटा लेते। इसे उदार दृष्टिकोण और बड़े फैसलों के द्वारा राजनीतिक ढंग से ही निपटाया जा सकता है।

माया: आप शुरू से ही समझौते के विरोध में थे? किन कारणों से आपने बाद में परिस्थितियों से समझौता कर लिया?

बादल: हां, मैं समझौते के खिलाफ था। मैं इसके लिए कुछ जरूरी पूर्व शर्तें लगाना चाहता था और मैंने समझौता होने के पहले और बाद में अपने विचार भी रखे थे। समझौता एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं था। पार्टी के सदस्य के नाते मैं जो कुछ भी कर सकता था, मैंने किया।

माया: आप संत लोंगोवाल के करीबी और विश्वासपात्र थे। कहा तो यह जाता है कि लोंगोवाल को आपने ही उठाया था। फिर यह कैसे हो गया कि लोंगोवाल ने समझौता करने के पहले आपसे मशविरा भी नहीं किया।

बादल: नही, उन्होंने मुझसे सलाह की थी। मैं कुछ पूर्व शर्तें चाहता था और पार्टी का भी यही मत था। लेकिन पता नहीं बरनाला और बलवंत सिंह उन्हें प्रभावित करने में कैसे कामयाब हो गये?

माया: पिछले चुनाव में अकाली दल की भारी जीत हुई थी। आप क्या सोचते हैं, ये वोट लोंगोवाल के बलिदान के लिये थे या उनके उत्तराधिकारी बरनाला को दिये गये थे या फिर यह पंजाब समझौते पर लोगों के समर्थन की मुहर थी?

बादल: साफ बात तो यह है कि चुनाव दिखावटी थे। केंद्र ने पहले ही सत्ता अकाली दल को सौंपने का मन बना लिया था।

माया: लेकिन लोंगोवाल समझौते के लिए आपको अपने साथ दिल्ली नहीं ले गये?

बादल: नहीं, और मैं जाता भी नहीं। यह मेरा सिद्धांत है कि मैं हर मामले में अपने विचार ईमानदारी से देता हूं और वे मैं दे चुका था। इसके बाद मुझे किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी।

माया: आपने विधायक दल के नेतृत्व के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ा?

बादल: मैंने सोचा कि बरनाला और बलवंत समझौते को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं, क्योंकि वे एक 'पार्टी (समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले) हैं। मैं यह भी जानता था कि समझौते को लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसका दोष मेरे ऊपर आये।

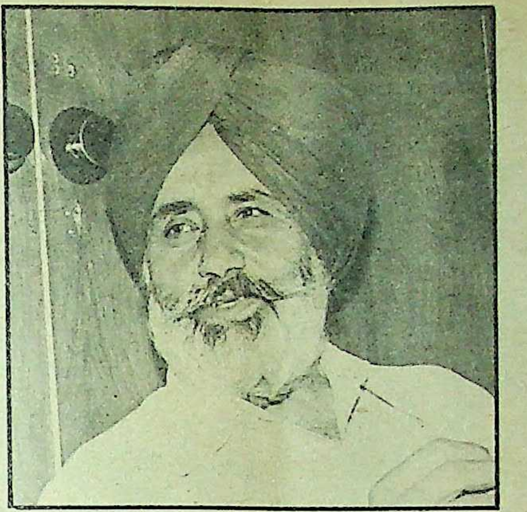

माया: यदि आपने बरनाला को अपना नेता मान लिया था, तो फिर मंत्रिमंडल में क्यों शामिल नहीं हुए?

बादल: यह जरूरी नहीं है कि हर कोई मंत्री बने।

माया: पार्टी में दो फाड़ के क्या कारण थे?

बादल: मुख्य कारण स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजना था। आनंदपुर साहिब सम्मेलन में मैंने बरनाला को साफ कह दिया था कि वह केंद्र के निर्देश पर कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर में सेना न भेजें, पर उन्होंने यही किया।

माया: पंथिक एकता की अब क्या सभावनाएं हैं?

बादल: हम पंथिक एकता तो चाहते हैं, परंतु आधारभूत मुद्दों और मूल्यों की कीमत पर नहीं।

माया: ये 'आधारभूत मूल्य' क्या हैं?

बादल: वही, स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश।

माया: लेकिन जो कुछ हो चुका है, अब उसे उलटा तो जा नहीं सकता?

बादल: लेकिन पंथिक एकता का यह मतलब नहीं है कि उन एक दो लोगों को, जिनके कारण उसमें दरार पड़ी, किसी समझौता वार्ता में शामिल किया जाये।

माया: क्या यह केवल बरनाला का फैसला था?

बादल: नहीं, बलवंत सिंह और बरनाला दोनों का ही। साथ ही केंद्र भी उनके साथ था।

माया: क्या आप यह नहीं सोचते कि पार्टी में ऐसे बहुत से महत्वाकांक्षी नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसी वजह से पार्टी में दरार भी पड़ी।

बादल: नहीं, यह सही नहीं है।

माया: भविष्य में आपकी क्या योजना है?

बादल: केंद्र के विरुद्ध संघर्ष।

माया: यह संघर्ष किस तरह का होगा?

बादल: शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक।

माया: क्या आप नहीं सोचते हैं कि आतंकवाद आज पंजाब की जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन गया है?

बादल: हर चीज की निंदा करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब तक केंद्र आतंकवादियों की निंदा बंद नहीं करेगा, आतंकवाद जारी रहेगा।

माया: आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याओं को आप किस तरह देखते हैं?

बादल: निंदा इसका समाधान नहीं है। यदि मैं इसकी निंदा भी कर दूं, तो इससे किसी की सहायता नहीं होगी।

माया: स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों के सफाये के लिए और कौन-सा रास्ता सुझायेंगे?

बादल: इसका फैसला मुझे नहीं करना है, क्योंकि हर सिख को मंदिर के अंदर रुकने का अधिकार है।

माया: पंजाब समस्या के समाधान के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं?

बादल: इसे सुलझाना केंद्र के जिम्मे है।

माया: आपके खयाल से केंद्र को क्या करना चाहिए?

बादल: केंद्र को सिखों का विश्वास अर्जित करना चाहिए और मेरे बताये पांच सूत्रों पर अमल करके वह समाधान की ओर एक कदम बढ़ा सकता है।

माया: यदि मौजूदा स्थितियों में आपसे सरकार बनाने को कहा जाये, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी?

बादल: नहीं, मेरे द्वारा सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी परिस्थिति में मैं केंद्र द्वारा सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं करूंगा।

माया: क्या आपके हाल के बयानों से आपकी धर्मनिरपेक्ष छवि खराब नहीं हुई है?

बादल: नहीं, किसी भी तरह नहीं। और यदि सच बोलने से छवि खराब भी होती है, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता।

माया: आम तौर पर सभी प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया है, सिवाय गुरचरण सिंह तोहड़ा के। तोहड़ा को रिहा न करने के क्या कारण हो सकते हैं?

बादल: क्योंकि केंद्र सरकार तोहड़ा की कूटनीतिक क्षमता से घबराती है। तोहड़ा एक ही झटके में केंद्र द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बेकार कर सकते हैं।

माया: राज्यपाल शासन की अवधि की समाप्ति के बाद आप किस तरह की सरकार बनाने का सुझाव देंगे?

बादल: ये सब प्रश्न बाद के हैं। चूंकि यह मसला केंद्र सरकार ही हल कर सकती है, इसलिए राज्य में किसी सरकार के बनने-न-बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

माया: यदि केंद्र आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा, तो क्या आप ऐसा करेंगे?

बादल: अब हम केंद्र पर और ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। मेरी चार सूत्रीय (१. आम माफी, २. जोधपुर जेल से बागी, फौजियों की रिहाई, ३. इन फौजियों की पुनर्वास व्यवस्था, काले कानूनों की वापसी और, ४. ८४ के दंगों के लिए दोषी लोगों को सजा) शर्तों के पूरे होने पर ही बातचीत हो सकती है।

साक्षात्कार/बलवंत सिंह

मैंने हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन किया

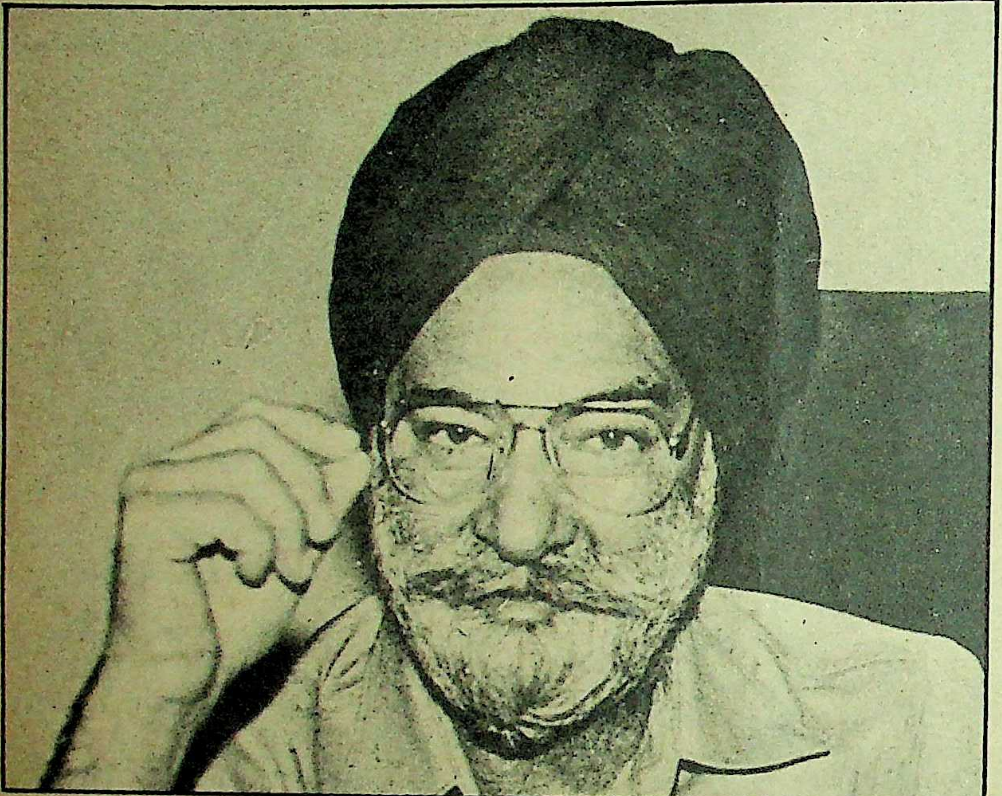

बलवंत सिंह कद में छोटे, किंतु लंबी पहुंच वाले व्यक्ति हैं। वह धनी किसान और बड़े व्यापारी हैं। वह केंद्र के चहेते के रूप में जाने जाते हैं और इससे न केवल उनका राजनीतिक कैरियर दुष्प्रभावित हुआ है, बल्कि बरनाला सरकार को भी नुकसान हुआ है। उन पर आरोप है कि अर्जुन सिंह से मिलकर उन्होंने केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए बरनाला पर दबाव डाला था और अकाली दल में दो फाड़ होने का यह एक प्रमुख कारण भी था। कहा जाता है कि इस समय राजनीति में अपनी पकड़ बढ़ाने के बजाय वह अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। संभव है वह बहुत जल्दी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। पंजाब की स्थिति इतनी अस्थिर है कि पक्की तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। यदि केंद्र उन्हें कोई निर्णायक काम सौंपता है, तो वह फिर लौट सकते हैं। प्रस्तुत हैं, 'माया' के साथ उनकी बातचीत के प्रमुख अंश :

माया: पंथिक एकता की क्या संभावनाएं हैं?

बलवंत : हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं आ रहा। हम शिरोमणि अकाली दल के सिद्धांतों और कार्यक्रम के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से एकता चाहते हैं। हमारा मतलब हैं कि दोनों दलों का विलय कर दो। इसके बाद विधायक दल के नेता और अकाली दल के अध्यक्ष के नये चुनाव कराये जायें। इन चुनावों में उन विधायकों को भी वोट देने का अधिकार होगा, जिन पर अदालत में दलबदल कानून के तहत केस चल रहे हैं।

माया : आपके खयाल से केंद्र के लिए क्या बेहतर होगा—निलंबित विधानसभा को फिर से बुलाना, नये चुनाव कराना या राज्यपाल शासन की अवधि बढ़ाना?

बलवंत : पंजाब जैसे गड़बड़ी वाले प्रदेश में नये चुनाव कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राज्यपाल शासन में स्थिति और बिगड़ी है, इसलिए उसकी अवधि बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है।

माया : लेकिन यदि नये चुनाव की घोषणा होती है, तो क्या अकाली दल बहुमत हासिल कर पायेगा?

बलवंत : उसी स्थिति में जब यह एक हो जाये। बंटा हुआ अकाली दल सरकार बनाने योग्य नहीं होगा।

माया : आप क्या सोचते हैं? यदि विधानसभा दुबारा बुलायी जाती है, तो बरनाला पर्याप्त समर्थन जुटा पायेंगे?

बलवंत : हमने तय किया है कि शिरोमणि अकाली दल का नेता विधायक दल का भी नेता होगा।

माया : बरनाला के बारे में क्या विचार हैं?

बलवंत: नहीं, क्योंकि उन पर स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजने और पंथ को गुमराह करने के आरोप हैं।

माया : यह अकसर कहा जाता है कि बरनाला सहित सभी अकाली सरकारों को गिराने में आपका हाथ रहा है। इसमें कितनी सचाई है?

बलवंत : यह सब मेरे खिलाफ झूठा प्रचार मात्र है और इसके लिए मुख्य रूप से पत्रकार ही जिम्मेदार हैं। मैंने कभी यह सब नहीं किया और हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन किया है।

माया : क्या कारण हैं कि इस तरह के आरोप आप पर ही लगाये जा रहे हैं?

बलवंत : बरनाला के दुबारा मुख्यमंत्री बनने का तो अब प्रश्न नहीं है। संयुक्त अकाली दल के लोग जानते हैं कि यदि पार्टी नेता के लिए नये चुनाव हुए, तो मै अपने लिए पर्याप्त समर्थन जुटा सकता हूं। अतः ये आरोप लगाकर बरनाला की तरह मेरा भी पत्ता साफ करना चाहते हैं।

माया : इस बात की सफायी में आप क्या कहेंगे कि हर अकाली मंत्रिमंडल में आप शामिल थे?

बलवंत : मैं यह कहूंगा कि हर मुख्यमंत्री सोचता था कि एक आदमी (यानी मैं) ऐसा है जिसे अपने साथ रखना चाहिए।

माया : हर मंत्रिमंडल में आप दूसरे नंबर के मंत्री थे। फिर क्या कारण है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सके?

बलवत : इस गुटबाजी वाली राजनीति में मुझे मत खींचिये।

माया : यह आम धारणा है कि राजनीति में आप अपने धंधे को बढ़ाने के उद्देश्य से आये। इसमें कितनी सचाई है?

बलवंत: यह सच नहीं है। मौका मिलते ही मैं राजनीति छोड़कर अपने धंधे में वापस लौट जाऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण कारणों से अभी ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है।

माया : सभी धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया गया है, मगर 'गुरचरण सिंह टोहड़ा अभी भी अंदर हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है?

बलवंत : पहली बात तो यह है कि केंद्र उनकी राजनीतिक क्षमता से डरती है। वह जानता है कि टोहड़ा उनकी सभी कोशिशों को एक ही झटके में बेकार कर सकता है। दूसरे-टोहड़ा को न छोड़ने का मतलब है। केंद्र जोधपुर जेल में बंद कैदियों को रिहा नहीं कर रही है, क्योंकि वह भी उसी मामले में हिरासत में लिए गये थे।

माया : इस समय राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हैं—बादल, बरनाला, टोहड़ा या बलवंत सिंह?

बलवंत : मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा (लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस समय वह बादल को सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मानते हैं)।

भी समाधान की प्राप्ति में आड़े आये हैं। राज्य में बढ़ रही हत्याओं के चढ़ते ग्राफ पर भी केंद्र की नजर है। १९८६ में ३२४ हिंदुओं सहित ५१७, १९८७ में ४७८ सिखों सहित ९१० लोग मारे गये थे। १९८८ के जनवरी माह में ही आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्याओं की संख्या २०० पार कर गयी है। १९८७ में ३२८ आतंकवादियों के मारे जाने और ३३७४ के गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद ऐसा हो रहा है। पुलिस के दावों के अनुसार १९८७ में हर दिन ३.७३ लोग मारे गये। अफवाहों के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ों में मरनेवाले ज्यादातर निर्दोष युवा सिख हैं और आतंकवादी फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इन अफवाहों का खंडन किया है और पंजाब में हिंसा न खतम होने के बारे में अपनी सफायी दी है। पुलिस का कहना है कि आतंकवादी खीझे हुए हैं और अब वह अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मानसिक युद्ध है। कुल मिलाकर कहना यह है कि रक्तपात जारी है और रुक नहीं रहा और सफाई से लोगों की जान बचेगी नहीं और न ही उन परिवारों को कोई सांत्वना मिलेगी जिनके सदस्य मारे गये हैं। प्रकाश सिंह बादल के रिहाई के सिवा कोई महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया।

> **पुलिस का दावा तो यहां तक है कि स्वर्ण मंदिर में किसी महिला के साथ बलात्कार या हत्या की घटना होने के बावजूद बाहर की गलियों में व्यापार पहले की तरह ही जारी रहता है। लोगों का व्यवहार इतना रूखा हो गया है कि जीवन की गरिमा तथा कीमत का अहसास खतम होने लगा है। कोई भी पंजाब के बारे में पढ़ना या बात करना नहीं चाहता। हत्याओं पर लोग कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते, मानो ये सब रोजमर्रा की घटनाएं हैं। शायद केंद्र ने भी इससे मुक्ति पा ली है।**

हृदयहीनता: कहा जाता है कि राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय और पुलिस महानिदेशक जूलियस रिबेरो ने गृहमंत्री बूटा सिंह से राजनीतिक कदम उठाने के लिए कहा है, लेकिन नयी दिल्ली और चंडीगढ़ के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लगातार हो रही हत्याओं को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यहां तक कि संवेदना-संदेश भी जारी नहीं किये गये। ऐसे लोग जिनकी जड़ें पंजाब में हैं या खास तौर पर सिखों में भी इस संबंध में हृदयहीनता ही नजर आयी। पुलिस का दावा तो यहां तक है कि स्वर्ण मंदिर में किसी महिला के साथ बलात्कार या हत्या की घटना होने के बावजूद बाहर की गलियों में व्यापार पहले की तरह ही जारी रहता है। लोगों का व्यवहार इतना रुखा हो गया है कि जीवन की गरिमा तथा कीमत का अहसास खतम होने लगा है। कोई भी पंजाब के बारे में पढ़ना या बात करना नहीं चाहता। हत्याओं पर लोग कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते, मानो ये सब रोजमर्रा की घटनाएं हैं। शायद केंद्र ने भी इससे मुक्ति पा ली है। जब लोगों ने पंजाब के बारे में बात करना और पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर वह क्यों चिंता करें? कुछ राजनीतिक विरोधियों ने अपने ढंग से राग अलापा, मगर सुनता कौन? यहां तक कि प्रधानमंत्री ने चर्चित पदयात्रा से लौटे सुनील दत्त से भेंट तक नहीं की और स्वीडन में उन्होंने दावा किया कि भारत में सब बढ़िया है। पंजाब में हर रोज तीन आदमी मारे जा रहे हैं लेकिन सब बढ़िया है।

आखिरकार, केंद्रीय नेताओं को विचार करना होगा कि पंजाब में बंदूकों को चुप कराने में सफलता क्यों नहीं मिली? राजनीतिक और आर्थिक योजनाओं से कुछ नहीं हुआ। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी अकाली सरकार असफल हो गयी। सरबत खालसा, सर्वदलीय सम्मेलन, मोर्चे, रैलियां, जत्थे, राष्ट्रपति शासन और यहां तक कि आतंकवादियों से सख्ती से निपटने का खयाल भी थोथा साबित हुआ। हर तरह की राजनीति और हर तरह के पुलिस प्रयास, अकेले या मिलकर, आजमाये गये लेकिन सब बेकार। अत: यथास्थिति को क्यों न बना रहने दिया जाये? आतंकवादियों के हमलों में अपने सभी सगे-संबंधियों को खोने वाले एक पुलिस अधिकारी का कहना है, "यदि कारतूसों की कमी नहीं है, तो खून की भी नहीं।"

किसी के द्वारा जिम्मेदारी महसूस न करना ही पंजाब की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार है। साक्षात्कार (देखें बाक्स) में यह बात साफ झलकती है। केंद्रीय नेताओं द्वारा भावनाओं को व्यक्त न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती गांधी को जैल सिंह ने बचाया और राजीव गांधी को बूटा सिंह की ढाल ने बचा रखा है। आतंकवादियों की आड़ ने अपराधियों को अपने दुश्मनों को खतम करने का नया तरीका दे दिया है।

कहा जाता है कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस०एस० ब्रार की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि उन्होंने खाद बनाने वाली एक फर्म में चल रही धांधली को पकड़ा था। यह फर्म एक बड़े नेता की है। निश्चित रूप से जिस तरह सीमा पार से आतंकवादी धन और शस्त्र प्राप्त करते हैं, उसी तरह से स्मगलर और छोटे-मोटे अपराधी भी इस स्थिति का फायदा उठाते होंगे।

शाम साढ़े छह बजे अपने घर के दरवाजे बंद कर लेने वाले अमृतसर के एक निवासी का कहना है, "पंजाब में भगवान और गुरु के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। अत: जो भी कुछ राज्य में हो रहा है, भगवान की मरजी से।" पूरी संभावनाएं हैं कि केंद्र भी 'तथास्तु कह देगा।

—अमृतसर से अभय अग्रवाल और सुनयना अरोड़ा

क्या बावा सचमुच फरार हुआ?

पंजाब के कस्बों और राजधानी चंडीगढ़ में आजकल इस बात की जोरों से चर्चा है कि हरजिंदर सिंह जिंदा का साथी खूंखार आतंकवादी सतनाम सिंह बावा मारा गया है, जिंदा है अथवा पुलिस का मुखबिर बन गया है।

स्मरणीय है कि ९ जनवरी को सतनाम सिंह बावा पुलिस की गिरफ्त से उस समय भाग निकला था, जब उसे अमृतसर जिले के उड्डन गांव (थाना—लोपोक) लाया जा रहा था।

पुलिस ने दावा किया था कि जोरदार मुठभेड़ के बाद आतंकवादी बावा को छुड़ाकर ले गये, जबकि सी०आर०पी०एफ० सूत्रों के अनुसार जब पुलिस उड्डन गांव में हथियार बरामद करने के लिए उसे साथ लेकर जा रही थी, तभी बावा चकमा देकर भाग निकला। इस संवाददाता को एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसका दावा है कि उसने बावा को फरार होने की खबर उड़ने के कुछ घंटे बाद गुरदासपुर जिले के एक फार्म हाउस में पुलिस के संरक्षण में देखा था। इसका कहना था, "यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अन्य लोगों की भांति मैं भी यही समझता था कि पुलिस ने बावा को जानबूझकर मार डाला और फिर उसके भाग जाने की खबर उड़ा दी। ए०आई०एस०एस०एफ० के एक कार्यकर्ता गुरजीत सिंह भी उक्त विचार से सहमत हैं। अकाली दल—लों के अध्यक्ष सुरज़ीत सिंह बरनाला तथा अन्य ने भी अपने अपने साक्षात्कारों में कुछ इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की हैं।

जब बावा के जीवित रहने की अफवाह उड़ी, तो छानबीन करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी लगा कि बावा न तो भागा है और न ही मरा है, किन्हीं विशेष कारणों से जानबूझ कर बावा के भागने की कहानी तैयार की गयी। इन सब तथ्यों को देखकर तो यह स्पष्ट है कि पंजाब में सब वैसा नहीं है जैसा कि लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। कुछ आतंकवादी जिन्हें लोग मानते हैं कि वे मुठभेड़ में मारे गये, हो सकता है कि वे पुलिस संरक्षण में पूछताछ का सामना कर रहे हों और कुछ, जिन्हें माना जा रहा है कि वे पुलिस संरक्षण में हैं, हो सकता है कि वे वहां हों ही न। ■

साढ़े दस करोड़ की टांगें

इटली के फुटबाल क्लब 'एसी मिलान' ने १९८७ में यूरोप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ठहराये गये रूड गिलिट की टांगों का ८२ लाख डालर अर्थात १० करोड़ ६६ लाख रुपए में बीमा कराया है। गिलिट से पूर्व सबसे महंगी टांगों के लिए अर्जेंटीना के फुटबाल खिलाड़ी डिएगो माराडोना विख्यात थे। नेपल्स ने माराडोना की टांगों का बीमा ६६ लाख डालर अर्थात ८ करोड़ ५८ लाख रुपए में कराया था।

पश्चिम जर्मनी के एक जीवशास्त्री बनार्ड मीयेर ने दावा किया है कि उन्होंने वानर जाति के एक नये प्राणी का पता लगाया है। मीयेर को यह प्राणी हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीप में पेड़ों पर झूलते मिला। १९३० के बाद यह पहला मौका है, जब वानर प्रजाति के किसी नये प्राणी का पता लगाया गया।

जापान के मियाजाकी के रेल तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने ५१७ किमी० प्रतिघंटा की रफ्तार से चलनेवाली रेलगाड़ी बनाने में सफलता हासिल की है। इस गाड़ी का नाम मगलेव रखा गया है। यह गाड़ी सुपर कंडक्टीविटी चुंबक लगी रेल पटरियों पर दौड़ेगी, जिसके खिचाव से यह रेलगाड़ी हवा मे तैरती हुई चलेगी। इस गाड़ी के यात्रियों को हवाई जहाज की तरह अपनी कमर पेटियों से बांधनी पड़ेगी। जापान में अभी ३०० किमी० प्रतिघंटे की रफ्तार से बुलेट रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं।

देश के १८ उच्च न्यायालयों में १४ लाख, ८४ हजार २ सौ २० मुकदमे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की संख्या सर्वाधिक अर्थात २ लाख ८८ हजार ८० है।

देश में १९८५ और १९८७ के बीच एक अरब ४० करोड़ रुपए मूल्य के २० हजार ७५० टन सिक्कों का आयात किया गया।

पूरे देश में पशु-पक्षियों की १४६ प्रजातियां लुप्तप्राय हो गयी हैं। इस समय देश में वन्य जीवन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ६३ और अभयारण्यों की संख्या ३५८ है।

उत्तर प्रदेश में २० हजार या उससे अधिक आबादी वाले ५५ कस्बे ऐसे हैं, जहां अभी तक गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा है।

गत वर्ष पूरे देश में २ लाख ४० हजार टन नहाने के साबुन का उत्पादन हुआ। यदि नहाने के साबुन की एक बट्टी ५० ग्राम की मानी जाये, तो गत वर्ष एक भारतवासी के हिस्से में साल भर के लिए सिर्फ ७ बट्टी साबुन आया।

चीन सरकार ने गबन और रिश्वत जैसे अपराधों के लिए सजा-मौत मुकर्रर की है।

भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने १८८ व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे शुरू किये हैं, इस लपेटे में १०४ सरकारी कर्मचारी भी आये हैं, जिनमें ५६ राजपत्रित अधिकारी हैं। जिन बड़े अफसरों के खिलाफ मुकदमें शुरू हुए हैं उनमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस कार्पोरेशन लिमिटेड के शाखा प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।

पटियाला में आयोजित भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक चैंपियनशिप में दो नये रिकार्ड बने हैं। २० किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्यालय के मोहन लाला ने यह दूरी एक घंटे ३७ मिनट और ५० सेकेंड में पूरी करके पिछला रिकार्ड (एक घंटे ३९ मिनट ३ सेकेंड) तोड़ दिया है। इसी प्रकार केरल की जेली जेम्स ने ४२.१२ मीटर दूर तक भाला फेंककर पिछले ३९.६६ मीटर दूरी तक भाला फेंकने के रिकार्ड को तोड़ दिया है।

हैदराबाद के राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा० ए०के० गौड़ ने रहस्योद्घाटन किया है कि पृथ्वी के धरातल के १५० किलोमीटर नीचे हो रही हलचलों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की ओर ५.५ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से खिसक रहा है। इसी कारण अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है और प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है।

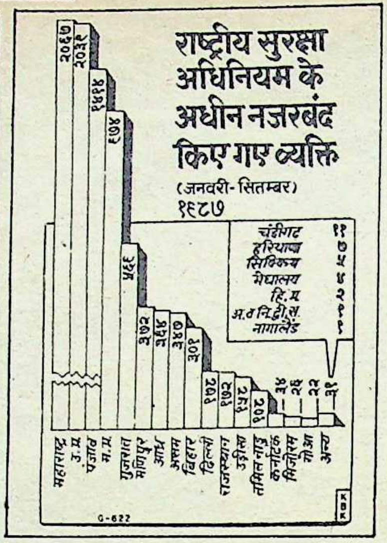

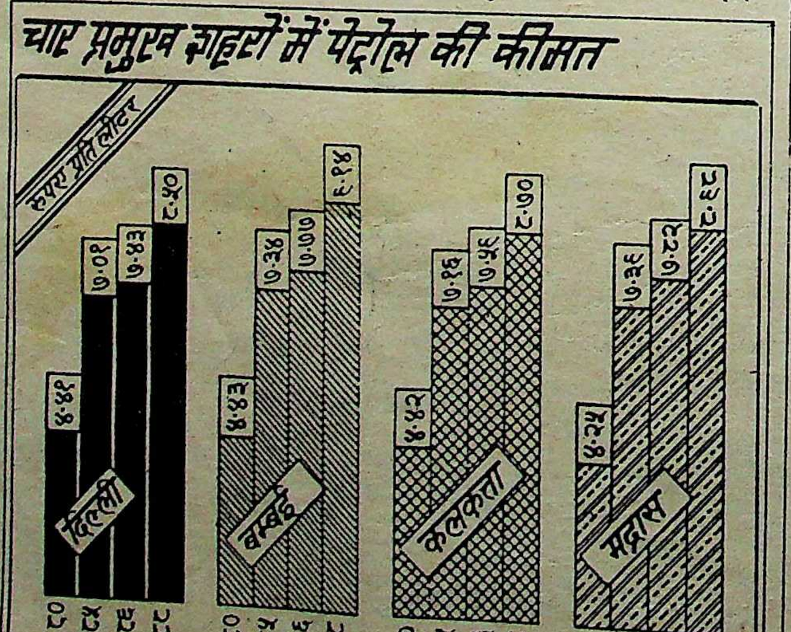

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल के लिए समस्याग्रस्त घोषित २३ हजार ८२ गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गत वर्ष ८ करोड़ ७० लाख रुपए दिये थे, लेकिन उसने सिर्फ इसका १३ प्रतिशत अर्थात एक करोड़ २० लाख रुपए खर्च किये।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सूखे से पीड़ित ६० लाख खेतिहर मजदूरों और २९ लाख लघु किसानों को राहत देने के लिए ग्राम विकास और लघु सिंचाई मद में कुल १०० करोड़ ६२ लाख रुपए दिये थे, लेकिन वह केवल १४ करोड़ ५१ लाख रुपए ही खर्च कर सकी।

भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के अंतर्गत गत नवंबर मास तक विशेष रोजगार योजनाओं में ४८ हजार मजदूरों को काम मिला जबकि इसी दौरान हरियाणा में ५७ हजार, गुजरात में ११ लाख ८९ हजार और राजस्थान में १० लाख लोगों को सूखा राहत योजनाओं में रोजगार मिला।

पाक सरकार ने घोषणा की है कि वह १५ करोड़ डालर के हथियार विदेशों से खरीदेगा।

खालिस्तान पंथक कमेटी ने इस २६ जनवरी को खालिस्तान का जो नक्शा प्रसारित किया उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर सारा भारत खालिस्तान होगा। स्वर्ण मंदिर से हाइड्रोजन गुब्बारों द्वारा खालिस्तानी झंडे भी उड़ाये गये।

सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी महिला के साथ विवाह की कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं है। न ही ऐसी दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता मिलने का हक है। एक और फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवश्य स्वीकार किया कि दूसरी शादी से पैदा संतान को गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है।

—संयोजन : विनोद मिश्र

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्ष्या भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्ष्या के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठाले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यूब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के इन्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्ष्या मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सावधान-वाणीः अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

इलाहाबाद लोकसभा सीट

दांव पर – राजीव की इज्जत, राजा का भविष्य

इलाहाबाद अब मात्र लोकसभा की सीट नहीं, बल्कि इसने देश के भावी रुख को निर्धारित करने की हैसियत हासिल कर ली है। यहां कांग्रेस और विपक्ष के बीच पहला ऐसा चुनावी युद्ध होगा, जिसमें यह तय होगा कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। यदि यहां से अमिताभ लड़ते हैं, तो इसकी भी परीक्षा होगी कि कांग्रेस और राजीव गांधी की छवि धूमिल हुई है या नहीं और यह भी तय होगा कि राजा मांडा कितने पानी में हैं। इस अहमियत को देखते हुए ही 'माया' ने एक सर्वे टीम को लगाया और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले यहां के पांच विधानसभायी क्षेत्रों के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। सर्वे में हमने ११ सवाल रखे थे, जिनमें निम्नलिखित दो सवाल काफी अहम थे :

० यदि श्री अमिताभ बच्चन के सामने वीपी सिंह, उनके कोई व्यक्ति तथा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा खड़े हुए, तो आप किसको वोट देंगे?

० आप राजीव गांधी, वीपी सिंह, अमिताभ बच्चन में से किसको ज्यादा ईमानदार मानते हैं?

इन दोनों सवालों में से पहले सवाल पर सर्वाधिक मत अमिताभ बच्चन को और दूसरे सवाल पर वी०पी० सिंह को मिले हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बोफोर्स के नाम से अधिकांश लोग नावाकिफ हैं। इस सर्वे में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी उभर कर आया कि जो लोग कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी को वोट देना नहीं चाहते, वे भी अमिताभ बच्चन को वोट देने के लिए तैयार हैं।

लेकिन सर्वे एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है वे जटिलताएं जो चुनाव के ऐन मौके पर उभरती हैं। इसलिए हमने सत्ता के करीबी सूत्रों के जरिये उन मुद्दों, राजनीतिक दांवपेचों और समीकरणों की भी थाह ली है जो इस चुनाव में भूमिका निभायेंगे। प्रस्तुत है, विश्लेषण :

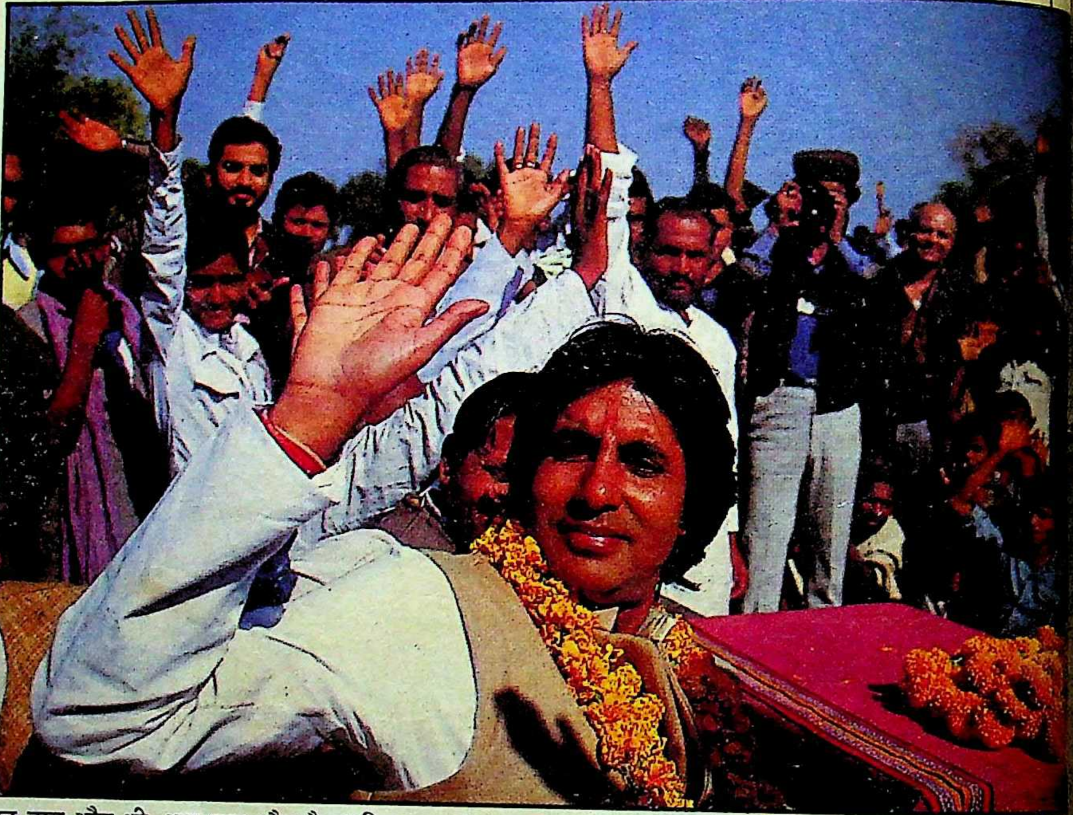

तब बात और थी, अब बात और है: अमिताभ बच्चन

राजनीतिक जीवन-मरण का सवाल: राजीव गांधी और सोनिया गांधी

छाया: मनमोहन शर्मा

उम्मीदवार
हेमवती नंदन बहुगुणा
को विज
चुनाव चि
दिलदार कं.

बदला लेने की तैयारी: हेमवती नंदन बहुगुणा

तकदीर का फैसला: एक सभा में वी०पी० सिंह

छाया: मनमोहन शर्मा

इलाहाबाद से चुने गये सांसदों में अमिताभ बच्चन का नंबर दसवां है। इस्तीफा देने वाले वह यहां के तीसरे सांसद हैं। पिछले दोनों व्यक्ति भी कांग्रेस के ही टिकट पर चुने गये थे, लेकिन उनके इस्तीफे देने की परिस्थितियां भिन्न थीं। वे मुख्यमंत्री चुन लिये गये थे, इसलिए उन्हें यह सीट खाली करनी पड़ी थी, जबकि १७ जुलाई, १९८७ को अमिताभ बच्चन ने भिन्न परिस्थितियों में इस्तीफा दिया था। वक्त की बात है कि इस्तीफा देने वाले पिछले दोनों व्यक्ति अब अमिताभ बच्चन के परम राजनीतिक शत्रु हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा उनसे चुनाव में असफल टक्कर ले चुके हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बदौलत उन्हें संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है।

अब इलाहाबाद की इस ऐतिहासिक लोकसभायी सीट के लिए उपचुनाव होना है, जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। यह इसलिए नहीं कि यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित कर चुके हैं, बल्कि इसलिए कि यह सीट अब वर्तमान प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल हो गयी है और विश्वनाथ प्रताप सिंह का भविष्य इस पर टिका है। बोफोर्स के तूफान के कारण राजीव गांधी की लोकप्रियता और छवि पर प्रश्नचिह्न लगा है तथा इसने सारे देश को उद्वेलित कर रखा है। इसी तूफान के कारण अमिताभ बच्चन को इस्तीफा देना पड़ा है—और इस तूफान के जनक वीपी सिंह हैं। इसलिए निर्णायक युद्ध इसी उपचुनाव को माना जा रहा है। लोकदल-अ के महासचिव सुब्रह्मणयम स्वामी के कथन से यही ध्वनि निकलती है, "इलाहाबाद का यह चुनाव सरकार और कांग्रेस के तमाम घोटालों के खिलाफ एक जनादेश होगा।" राजनीतिक प्रेक्षकों का मत है कि इस चुनाव के नतीजे का दूरगामी प्रभाव होगा। इससे मतदाता के रुख का पता चलेगा और पूरा देश नहीं, तो हिंदी-क्षेत्र इससे अवश्य प्रभावित होगा। यही क्षेत्र भारतीय राजनीति का भविष्य-नियंता है। इसी क्षेत्र के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में है। यदि इस चुनाव में कांग्रेस जीतती है, तो वीपी सिंह के देशव्यापी अभियान की भ्रूणहत्या को कोई नहीं टाल सकता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक का इशारा इसी ओर था। इस चुनाव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने 'माया' से कहा, "हां, राजा के भाग्य का

प्रोटीन देना. और इसीलिए मैंने उसके टाइम-टेबल में शामिल कर लिया है चीज़ को.
दरअसल चीज़ में प्रोटीन है ही इतना ज़्यादा कि खाने में मीट तक की कमी पूरी कर दे.
और स्वादिष्ट इतना कि यह मेरे बेटे की ज़बान पर चढ़ सा गया है.
इसलिए उसकी खुशी के लिए. मैं उसके लंच-बॉक्स में चीज की कोई न कोई चीज़ जरूर रख देती हूं. जी हां, अमूल चीज़ के व्यजन, जो मैंने खुद ही खोज निकाले हैं.

अमूल चीज़ रोल्स

(करीब २० रोल्स के लिए)

१५० ग्राम अमूल चीज़– कसी हुई ; १/२ कप दूध ; २ छोटे प्याज़–बारीक कटे हुए ; १ शिमला मिर्च–बारीक कटी हुई ; २ हरी मिर्च–बारीक कटी हुई ; २ सें.मी. अदरक का टुकड़ा–बारीक कटा हुआ ; १ चम्मच नमक ; ४०० ग्राम ताजी ब्रेड के स्लाइस–किनारे कटे हुए ; तलने के लिए थोड़ा तेल. चीज़ को दूध में मिलायें. फिर प्याज़, हरी मिर्च, अदरक और नमक भी डाल दें. इस मिश्रण को स्लाइसों पर फैला दें और हर स्लाइस को जैम-रोल की तरह रोल कर लें. हल्के लाल होने तक तलें. या बेक करना चाहें तो थोड़ा सा मक्खन लगाकर रोल्स को, मक्खन लगी ओवन-प्रूफ डिश में १०-१५ मिनट तक (१५०° सें. गैस २) बेक करें. एक सा सिकने के लिए एक बार पलट लें.

मकई और आलू

(६ के लिए सामग्री)

१५० ग्राम पनीर, ६ स्लाइस ब्रेड के– सिके हुए ; २ आलू–उबालकर छीले और मैश किये हुए ; १/२ कप मकई के दाने–उबले हुए ; ३ हरी मिर्च–कटी हुई ; १ चम्मच हरा धनिया–कटा हुआ ; २ चम्मच ताजी क्रीम या दूध की मलाई ; १ कप चीज़ सॉस ; ४-५ चम्मच अमूल चीज़–कसी हुई.

एक साथ मिला लें. स्वाद के अनुसार नमक मिलायें. इस मिश्रण को टोस्टों पर फैला लें. ऊपर से चीज़ सॉस डालकर, थोड़ी-थोड़ी कसी हुई चीज़ छिड़क लें. ओवन में रखकर १० मिनट तक 'बेक' करें (१९०° सें. गैस ५) गरम-गरम परोसें)

चीज़ सॉस

२ चम्मच अमूल मक्खन ; ३ चम्मच मैदा ; २ कप दूध ; १/२ चम्मच नमक ; १/४ चम्मच पिसी काली मिर्च ; १/२ चम्मच पिसी सरसों (मस्टर्ड पाउडर) ; १०० ग्राम अमूल चीज़–कसी हुई.
मक्खन को पिघला लें और उसमें थोड़ा मैदा डालकर अच्छी तरह मिलायें ताकि पेस्ट बन जाए. बुलबुले उठने तक गर्म करें. और ऊपर से धीरे-धीरे दूध डालते रहें. पकाते समय चम्मच से अच्छी तरह चलायें और थोड़ा गाढ़ा होने दें. अब इसमें नमक, काली मिर्च और पिसी सरसों डाल दें. कसी हुई चीज़ डालकर चम्मच से चलाते हुए पकायें जब तक चीज़ पिघल न जाए. बस, चीज़ सॉस तैयार.

चीज़ के १२० स्वादिष्ट व्यंजनों की 'अमूल चीज़ पुस्तिका' (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध) मंगाने के लिए इस पते पर लिखें : पो. ऑ. बॉक्स १०१२४, बम्बई ४०० ००१. कृपया साथ में रु. १५/- का क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, 'एडवर्टाइज़िंग एंड सेल्स प्रमोशन कंपनी' के नाम ज़रूर भेजें और अपना पूरा पता भी लिखें.

मेरे लाड़ले को सेहत का पहला पाठ सिखाती है पौष्टिक चीज़... अमूल चीज़.

अमूल चीज़

खाने में लज़ीज़...
सेहत की चीज़

बिक्री व्यवस्था
गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आणंद ३८८ ००१.

OPERATION
FLOOD

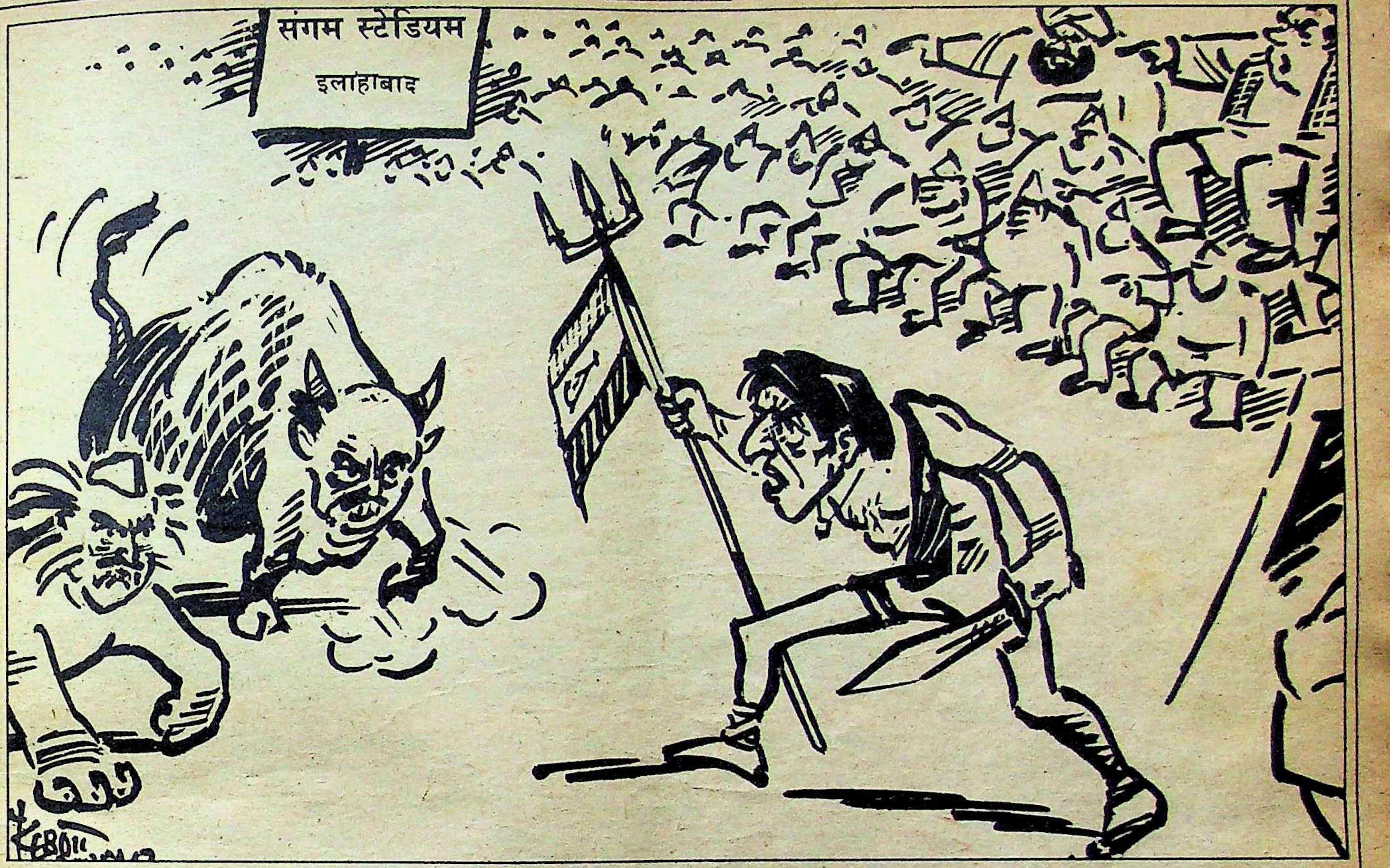

फैसला इलाहाबाद में ही होगा। यहां यदि वह खुद या अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवार को जिता नहीं पाये, तो उनका भविष्य चौपट है। जो अपने गढ़ में ही कुछ नहीं कर पायेगा, उस व्यक्ति को राजीव गांधी का विकल्प कौन मानेगा और कौन यह विश्वास करेगा कि जो आरोप वह राजीव गांधी पर लगा रहे हैं, वे सही हैं।"

यह चुनाव किस क़दर संवेदनशील हो गया है, ऐसा नहीं है कि इसका अहसास कांग्रेस और वीपी सिंह को नहीं है। सत्तारूढ़ दल के करीबी सूत्रों का कहना है कि ऐसी रणनीति बनाने का सुझाव दिया जा रहा है, जिससे यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रतीक न बन सके। इसके लिए एक सुझाव यह दिया जा रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति को खड़ा किया जाये। यदि उस व्यक्ति को जिता लिया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि जिस चुनाव को इतना तूल दिया जा रहा था, उसे एक सामान्य व्यक्ति के जरिये जीत लिया गया। यदि हार होती है, तो कहा जा सकता है कि हमने इस उपचुनाव को कोई महत्व ही नहीं दिया। जनमोर्चा के कुछ समर्थकों की भी यही राय है कि इस चुनाव को राजा अपनी आन-बान का सवाल न बनायें। लेकिन हालात ऐसे नहीं लगते कि दोनों पक्ष कोई कोर-कसर छोड़ेंगे।

यदि इस चुनाव को सामान्यतया लिया जाता, तो इसे मार्च तक यह कह कर टाला नहीं जाता कि कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण चुनाव कराना संभव नहीं। क्या त्रिपुरा में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक थी? लेकिन राजनीति में ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं होता। बहरहाल, अब संभावना यही है कि मई-जून तक यह उपचुनाव हो जायेगा। तब तक रबी की फसल से किसान फारिग हो जायेंगे और प्रशासन हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाओं से निपट लेगा।

जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री और इलाहाबाद मंडल के प्रभारी गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से नयी-नयी योजनाओं की उद्घोषणाएं हो रही हैं और जिस तरह से अधूरे वादे दोहराये जा रहे हैं, उससे भी यह नहीं लगता कि इंका इस चुनाव को अमहत्वपूर्ण बनाकर चल रहा है

१७-१८ दिसंबर को दो दिन लगातार मुख्यमंत्री इलाहाबाद में रहे हैं। जमुना पार के क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के मकसद से मुख्यमंत्री ने अनेक घोंषणाएं की हैं। ऊर्जा मंत्री वसंत साठे भी जायजा लेने के लिए इलाहाबाद का दौरा कर चुके हैं।

प्रत्याशी की तलाश: लेकिन सवाल यह है कि इस कांटे की लड़ाई के लिए प्रत्याशी कौन हो? जाहिर है, निश्चित प्रत्याशी का तो चुनाव के ऐन मौके पर ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच अनेक नाम उछल रहे हैं। इन नामों में अमिताभ बच्चन, ललिता शास्त्री, सुनील शास्त्री, उड़ीसा के राज्यपाल बी०एन० पांडे, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के पुत्र अशोक वाजपेयी, एन०डी० तिवारी और उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय तक के नाम उल्लेखनीय हैं।

जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनके प्रत्याशी बनने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। २ फरवरी को सांसद बी०एल० शैलेश ने तो स्पष्ट कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री से बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी यह चुनाव नहीं लड़ने जा रहीं। हां, इलाहाबाद की जातीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का मत है कि सोनिया गांधी का नाम एक खास मकसद से उछाला जा रहा है। उनका मत है कि सोनिया गांधी का नाम इलाहाबाद की ब्राह्मण लाबी एक ख़ास रणनीति के तहत उछाल रही है। यह लाबी नहीं चाहती कि अमिताभ बच्चन फिर से इलाहाबाद से चुनाव लड़ें। लेकिन यह लाबी सीधे-सीधे इसका विरोध न करके प्रत्याशी के रूप में राजीव गांधी की पत्नी का नाम प्रचारित कर रही है, जिससे

अमिताभ बच्चन को रोका जा सके। यहां कांग्रेस-इ की ब्राह्मण लाबी पर केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी का वर्चस्व माना जाता है, जिनके पुत्र अशोक वाजपेयी स्वयं इलाहाबाद में टिकट के दावेदार हैं।

कुछ समय पहले ऐसी खबरें उड़ी थीं कि इंका स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री को प्रत्याशी बनाने जा रही है। तर्क यह दिया गया था कि शास्त्री भी यहां से दो बार (१९५७-६२) चुनाव लड़ चुके हैं और उनके पुत्र हरिकिशन शास्त्री भी १९६७ में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए शास्त्रीजी के प्रति श्रद्धा का लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन बाद में यह चर्चा ज्यादा नहीं चली। हां, स्वर्गीय शास्त्रीजी के पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री सुनील शास्त्री का नाम अब भी काफी चर्चा में है। स्मरणीय है कि सुनील शास्त्री ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का तीव्र विरोध किया था और उनकी निकटता राजा मांडा से बढ़ती जा रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने 'जनमोर्चा' का साथ छोड़ दिया था। सुनील शास्त्री के पक्ष में भी वही तर्क दिये जा रहे हैं, जो उनकी माताजी के पक्ष में दिये जा रहे थे।

किसी स्वतंत्रता सेनानी को लड़ाने का मत व्यक्त करनेवाले लोग राज्यपाल बी०एन० पांडे का नाम ले रहे हैं और साधारण प्रत्याशी से असाधारण चुनाव जीतने का तर्क देने वालों की राय में श्यामसूरत उपाध्याय और अशोक वाजपेयी उपयुक्त प्रत्याशी हैं। भूतपूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की काट के लिए वर्तमान वित्तमंत्री एन०डी० तिवारी का नाम ले रहे हैं। लेकिन प्रेक्षकों की राय है कि तिवारी का नाम लेने वालों का उद्देश्य यह चुनाव जीतना नहीं, एन०डी० तिवारी को परेशानी में डालना है।

अमिताभ बच्चन ? : यों तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में काफी समय से इलाहाबाद की दीवारें रंगी जा रही हैं, भूख हड़ताल हो रही है, ज्ञापन दिये जा रहें हैं, लेकिन जब से वह लक्षद्वीप में राजीव गांधी के साथ नव वर्ष मना कर लौटे हैं, तब से लगभग यह माना जा रहा है कि इलाहाबाद से वही प्रत्याशी होंगे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनके नाम की घोषणा के पहले बोफोर्स की रिपोर्ट पेश की जायेगी, जिसमें उनका निर्दोष साबित होना निश्चित माना जा रहा है। इस बीच उनकी 'शहंशाह' फिल्म भी धूम मचा चुकेगी। इसके बाद वह यह आह्वान करते हुए चुनाव मैदान में कूदेंगे कि हिम्मत हो, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह मुझसे इलाहाबाद का चुनाव लड़ें, जिससे जनता फैसला कर सके कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, वे सही हैं या झूठे हैं। सत्ता के करीबी लोगों का कहना हैं कि बोफोर्स से ही राजीव गांधी की छवि धूमिल हुई है और इस विवाद के केंद्र में अमिताभ बच्चन रहे हैं। इसी विवाद के कारण उन्हें इलाहाबाद की सीट छोड़नी पड़ी है, इसलिए वह यहां से जीतते हैं, तो इससे बढ़कर कांग्रेस और राजीव गांधी की कोई जीत नहीं हो सकती। फिर मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को तो पूरा भरोसा है कि अमिताभ को वह हर हालत में जिता लेंगे, "जब मैं राजनीति में नयी-नयी प्रवेश करने वाली मीरा कुमार को बिजनौर से लोकसभा का उपचुनाव जितवा सकता हूं, पार्टी के स्थानीय कार्य-कर्ताओं के विरोध के बावजूद हरिद्वार संसदीय उपचुनाव में राम सिंह को विजयश्री हासिल करवा सकता हूं, तो फिर अमिताभ तो अपने आप में एक संगठन हैं।" पूर्व विदेशमंत्री और कांग्रेस सांसद दिनेश सिंह को भी अमिताभ बच्चन की जीत में कोई शक नजर नहीं आता। उन्होंने अमिताभ बच्चन को मशविरा देते हुए 'माया' को बताया, "मैं समझता हूं कि अगर अमिताभजी चाहेंगे, तो पार्टी टिकट मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उन्हें चुनाव में भी सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ उन्हें दृढ़ निश्चय करना होगा कि राजनीति द्वारा जनसेवा में पूरा समय देना है।"

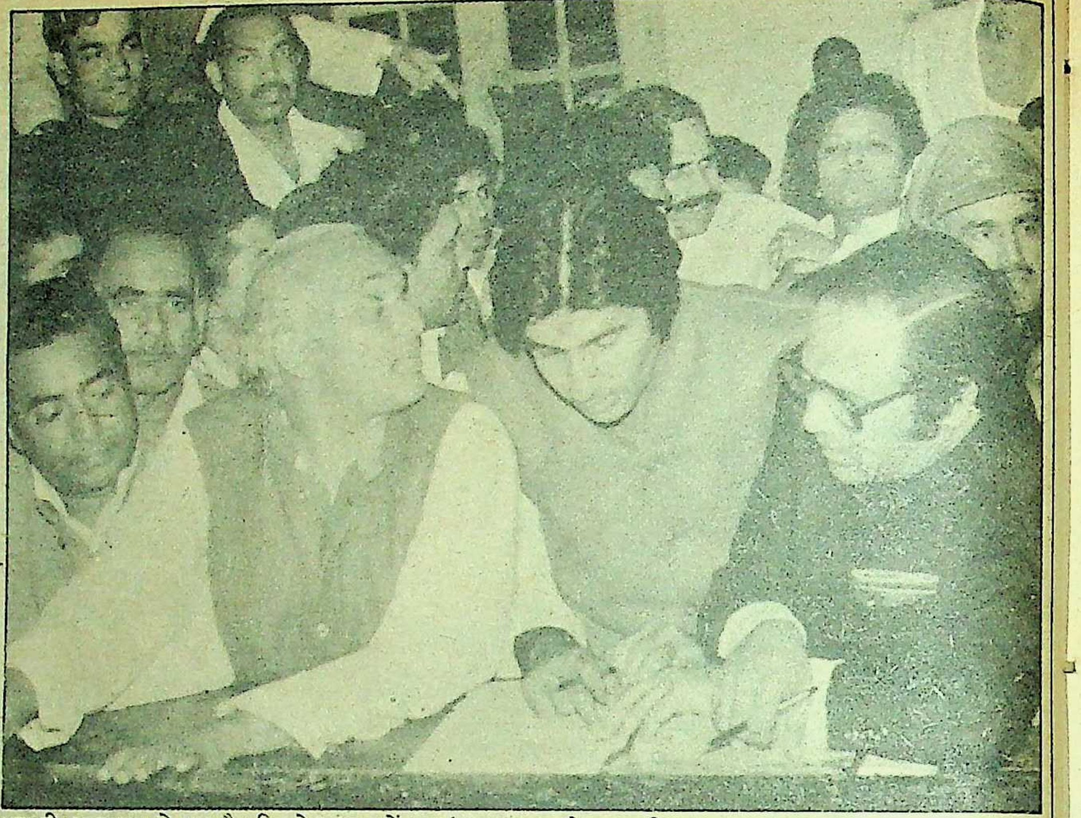

असली इम्तहान तो अब है : पिछले चुनाव में नामांकन पत्र भरते हुए अमिताभ

ऐसा नहीं लगता कि स्वयं अमिताभ बच्चन यहां से खड़े होने की इच्छा नहीं रखते। राजकोट में उन्होंने स्वयं कहा है कि वह राजनीति से बाहर नहीं हैं। इलाहाबाद में 'अमिताभ लाओ, इलाहाबाद बचाओ या इलाहाबाद बनाओ' के जो नारे लग रहे हैं और दीवारें रंगी जा रही हैं, उससे भी यह नहीं लगता कि यह बिना उनकी सहमति और सहायता के हो रहा है। खबर है कि कोई बंबई से पोस्टरों की एक खेप भी इलाहाबाद में पहुंच रही है।

जहां तक अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का सवाल है, 'माया' ने सर्वे आयोजित किया था (देखिए सर्वे)। इस सर्वे में 'माया' ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न तबकों के मतदाताओं से ११ सवाल पूछे थे। इस सर्वे से एक बात निर्विवाद रूप से सामने आयी है कि राजनीति के कारण चाहे अमिताभ बच्चन कितने ही बदनाम हुए हों, लेकिन फिल्मों के कारण वह आज भी लोकप्रिय हैं। लेकिन मात्र सर्वे के आधार पर कोई निश्चित भविष्यवाणी करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि उन राजनीतिक पेचीदगियों और पार्टी के आंतरिक समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं।

अमिताभ की बाधाएं : सत्ता के करीबी सूत्रों का कहना है कि अमिताभ का रास्ता उतना आसान नहीं है, जितना बताया जा रहा है। इन सूत्रों से बातचीत से जो निष्कर्ष निकलता है, वह कुछ इस प्रकार है :

पिछले आम चुनाव और इस उपचुनाव के मुद्दों में मूलभूत अंतर है। उस चुनाव में कांग्रेस को 'श्रद्धांजलि वोट' मिले थे और उसका लाभ अमिताभ बच्चन को भी मिला था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ८४ में से ८२ सीटों पर विजय हासिल की थी। केवल दो सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार जीते थे—बागपत में चौधरी चरण सिंह और एटा में

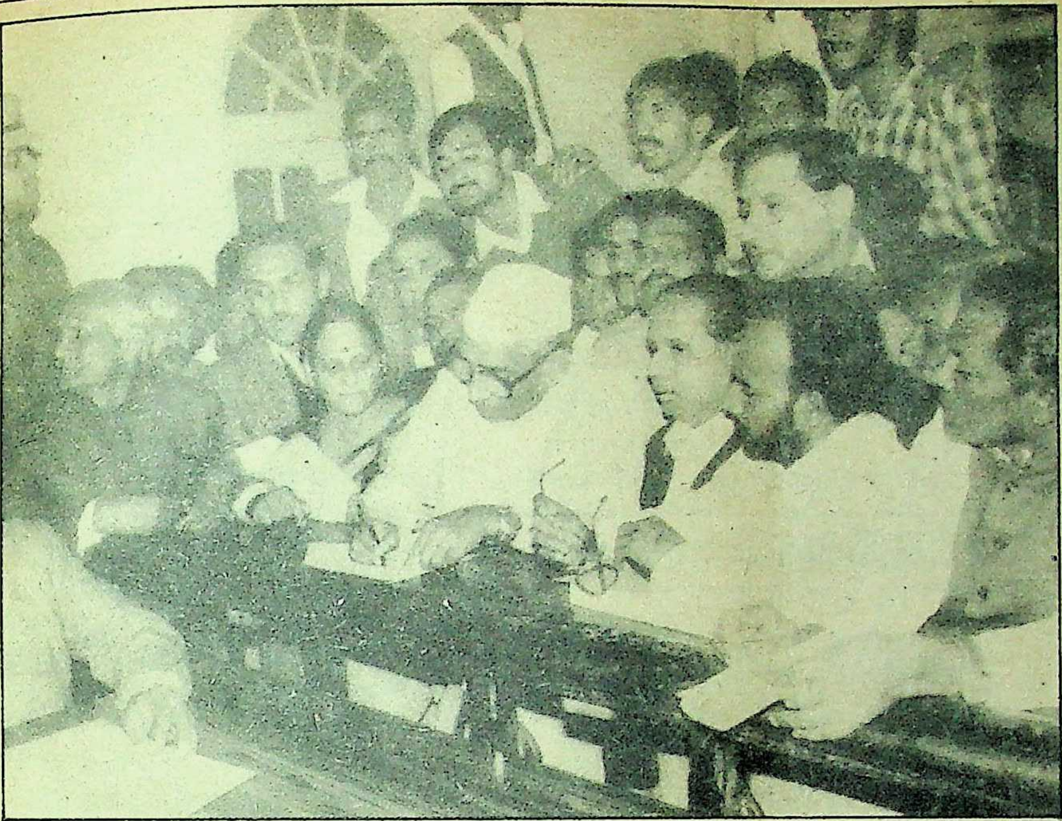

तब बात और थी: १९८४ में नामांकन दाखिल करते हुए बहुगुणा

प्यारे मियां। उस समय राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सारे देश ने राजीव गांधी के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। जनता ने उस समय राजनीति में नये खून का स्वागत किया था। राजीव की ही तरह अमिताभ भी जनता को आम पेशेवर नेताओं से अलग हटकर पढ़े-लिखे, ईमानदार और स्वभाव से युवक दिखायी पड़े थे, जिसमें गंदी राजनीति को साफ़-सुथरी बनाने की क्षमता और इलाहाबाद को 'रायबरेली-अमेठी' बना देने की सामर्थ्य नजर आ रही थी। इस आवेग में उनके सुपर स्टार होने ने सोने में सुहागे का काम किया था।

इन सूत्रों की राय है कि उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता की परीक्षा तो विधानसभा के चुनावों में थी, जिनमें अमिताभ बच्चन ने भरपूर चुनाव प्रचार किया था। इस चुनाव में स्वयं उनके निर्वाचन-क्षेत्र में कांग्रेस ने दो विधानसभायी सीटें खोयी थीं। करछना से के०पी० तिवारी हारे थे, जो उस समय मंत्री-पद पर थे। शहर-उत्तर से सरोज दुबे की हार हुई थी।

इन सूत्रों की राय में इलाहाबाद के स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी अमिताभ के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हैं। उनके क्षेत्र के ५ विधायकों में से दो विपक्ष के सदस्य हैं— करछना में कुंवर रेवती रमण सिंह (जनता) और शहर उत्तरी में लोकदल-अ के अनुग्रह नारायण सिंह। बचे कांग्रेस के तीन विधायक, जिनमें मेजा (सुरक्षित) के विश्रामदास यद्यपि अभी हैं तो कांग्रेस में, लेकिन वह विश्वनाथ प्रताप सिंह का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बचे दो विधायक, बारा क्षेत्र के रमाकांत मिश्रा और शहर दक्षिणी के सतीश चंद्र जायसवाल। ये दोनों विधायक शुरू में विश्वनाथ प्रताप सिंह के स्वागत-समारोह में बढ़-चढ कर हिस्सा ले चुके हैं। एक स्थानीय पुराने कांग्रेसी का कहना है कि यद्यपि अब ये कांग्रेस के साथ पूरी तरह से हैं, लेकिन लोग इन्हें संदेह की नजर से देखते हैं। ऐसी हालत में इनकी परेशानी यह है कि यदि यह चुनाव में पूरी मदद भी करते हैं, तो इनको श्रेय मिलने की संभावना कम है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के नौ ब्लाक प्रमुखों में यों तो ६ कांग्रेसी हैं, लेकिन इनमें से दो की विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ सहानुभूति है। मांडा के ब्लाक प्रमुख मंगल देव तो पूरी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हैं। करछना के ब्लाक प्रमुख फतेह बहादुर सिंह से सर्वे के दौरान बात हुई, तो उन्होंने कहा, "मैं वोट तो कांग्रेस के उम्मीदवार को दूंगा, लेकिन जीतेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह ही।"

अमिताभ की दूसरी समस्या है जातिवाद। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने 'माया' से कहा, "अमिताभ बच्चन के परिवार पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि वह जातिवादी हैं। अमिताभ की मां, पत्नी, उनके भाई, बंटी की पत्नी आदि विभिन्न जातियों के हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि उनको कायस्थ नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। दरअसल, यहां के कायस्थ जबरदस्ती उन पर लद गये हैं।" लेकिन ब्राह्मण लाबी को अमिताभ पूरी तरह कायस्थवादी और भाई-भतीजावादी नजर आते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मामा जगदीश राजन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, शांति स्वरूप भटनागर को राज्य का महाधिवक्ता, दयाशंकर भटनागर को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक बनवाया। स्थानीय महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जाति के लोगों की नियुक्ति तथा कांग्रेस के युवा संगठन में अजय श्रीवास्तव और शीतल कुमार के मनोनयन को उनकी जातिवादी राजनीति का ही नमूना बताया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके पत्रकार ससुर तरुण भादुड़ी की मध्य प्रदेश के पर्यटन निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति, साली रीटा वर्मा को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में खास रियायत, पत्नी जया भादुड़ी को नागरिक उड्डयन विभाग में सलाहकार की हैसियत दिलवाना आदि बातों के भी उदाहरण पेश किये जा रहे हैं।

ब्राह्मण लाबी के एक शुद्ध जातिवादी नेता तो इलाहाबाद की राजनीति में कायस्थों की लामबंदी के लिए अमिताभ को ही जिम्मेदार मानते हैं। वह कहते हैं, "कायस्थवाद-ब्राह्मणवाद जैसे वाद पहले ज्यादातर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ही सीमित थे, लेकिन अमिताभ के आने के बाद यह रोग परिसर के बाहर भी तेजी से फैला है।" बहरहाल कायस्थ लाबी का तर्क है कि इलाहाबाद के तीन विधानसभायी क्षेत्रों-शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और बारा में कायस्थों का वर्चस्व है, इसलिए यहां से कोई ग्लैमरस कायस्थ ही जीत सकता है। यह लाबी उदाहरण देती है कि यहां से चार 'कायस्थ' प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनमें एक सतीश चंद्र खरे (१९७४) हारे थे, बाकी— लाल बहादुर शास्त्री, हरिकिशन शास्त्री यहां से जीते हैं।

लेकिन इलाहाबाद के चुनाव इतिहास (देखिए बाक्स) पर नजर डालें, तो स्थिति दूसरी उभरती है। हालांकि पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को कायस्थ नेता कहना, उनकी तौहीन करना है। लेकिन फिर भी यहां हुए १० चुनावों में ५ बार ब्राह्मण प्रत्याशी जीते हैं और एक बार ठाकुर (विश्वनाथ प्रताप सिंह)। एक वरिष्ठ राजनेता का कहना है कि यदि अमिताभ बच्चन के लिए कायस्थवाद के आधार पर वोट मांगे गये, तो उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि बाकी जातियों के कांग्रेसी वोट जातियों में विभक्त हो जायेंगे।

पिछले चुनावों में बुद्धिजीवियों ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में माहौल बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसका कारण उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के प्रति आदर का भाव था। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी दिखायी नहीं पड़ती। इस वर्ग की शिकायत है कि अमिताभ ने चुनाव के बाद उनकी परवाह नहीं की। एक साहित्यकार की सख्त शिकायत थी कि महादेवी वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने न अमिताभ बच्चन पंहुचे

इलाहाबाद का चुनावी इतिहास

वर्ष १९८४ का लोकसभा चुनाव इलाहाबाद के चुनावी इतिहास में बेहद दिलचस्प चुनाव था। यशस्वी, कर्मठ राजनीतिक पृष्ठभूमिवाले और जोड़-तोड़ में माहिर हेमवती नंदन बहुगुणा के मुकाबले इलाहाबाद के मतदाताओं ने उस अमिताभ बच्चन के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया था, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नहीं थी और जो चुनाव सभाओं में बार-बार घोषणा कर रहा था कि वह राजनीति में 'जीरो' है। बहुगुणा के वास्तविक राजनीतिक संघर्ष से तपे तपाये व्यक्तित्व पर अमिताभ बच्चन की फिल्मी परदे की काल्पनिक 'सुपर मैन' की शख्सीयत भारी पड़ गयी थी। चुनावों की दृष्टि से बेजान पड़े इलाहाबाद शहर में उस वक्त नयी जान आ गयी थी। इलाहाबाद-वासियों में ऐसी जागृति उन चुनावों में भी देखने को नहीं मिली थी, जब यहां जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसी दिग्गज और जानी-मानी हस्तियां चुनावी दंगल में उतरी थीं। इलाहाबाद के चुनावी इतिहास में पहली बार अमिताभ बच्चन बनाम बहुगुणा चुनाव में ७० प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया, जबकि उसके पूर्व १९६७ (५३.१९ प्रतिशत) को छोड़कर किसी भी चुनाव में आधे से अधिक अर्थात पचास प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा तक नहीं लिया था। १९८१ के चुनावों में तो सिर्फ २६.५१ प्रतिशत मतदाताओं ने ही वोट डाले थे। लेकिन स्वयं अमिताभ बच्चन के अपने पद से इस्तीफा दे देने के कारण रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव होने की चर्चा, जिस तरह सरगर्म हो रही है, उससे लगता है कि यह उपचुनाव अमिताभ बनाम बहुगुणा चुनाव से भी अधिक दिलचस्प चुनाव साबित होगा। तब से अभी तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। देश के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, कल के दोस्त आज एक दूसरे के विरोधी बन गये हैं। इसी क्षेत्र से चुनाव जीतकर जो विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-इ के मुख्यमंत्री बने थे, वह आज राजीव गांधी की सत्ता को ललकार रहे हैं, इलाहाबाद को उनका गढ़ माना जाता है और उनकी मांद में ही होनेवाले इस उपचुनाव में उनका संपूर्ण राजनीतिक भविष्य दांव पर चढ़ गया है, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी परिवार के इस खानदानी इलाके में राजीव गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके बालसखा अमिताभ बच्चन यहां से विजयी जरूर हुए थे, लेकिन वह अपने मतदाताओं के नहीं, राजीव गांधी के प्रति प्रतिबद्ध थे। यहां से कांग्रेस-इ की ओर से कोई भी चुनाव लड़े, हार-जीत का यश-अपयश राजीव गांधी को ही मिलेगा। तीसरी ओर, इलाहाबाद के चंदन हेमवती नंदन बहुगुणा भी इस उपचुनाव पर अपनी बारीक नजर गड़ाये हुए हैं। जीवन के उत्तरार्द्ध में वह अपनी कर्मभूमि इलाहाबाद को किसी भी सूरत में अपने प्रभावक्षेत्र से निकलते नहीं देख सकते। अतः इस उपचुनाव में दिग्गजों का दंगल होगा। अभी चुनाव तिथि घोषित नहीं हुई है, किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है लेकिन प्रधानमंत्री सचिवालय में लगे कंप्यूटरों से लेकर विभिन्न पार्टियों के जमीन से जुड़े चुनाव-विशारद नेता तक सभी इलाहाबाद के मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र और पत्रिकाएं इस चुनाव क्षेत्र का सर्वेक्षण करा रही हैं। चुनावों का रुख पलट देनेवाली कोई प्रभावी लहर किसी के पक्ष-विपक्ष में नहीं है, ऊपर से सब शांत है, लेकिन भीतर-ही-भीतर जिस सरगर्मी से सभी पार्टियां यहां चुनाव तैयारियों में जुट गयी हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इलाहाबाद के मतदाता इस बेहद दिलचस्प चुनाव में बेहद दिलचस्पी लेंगे।

इलाहाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र

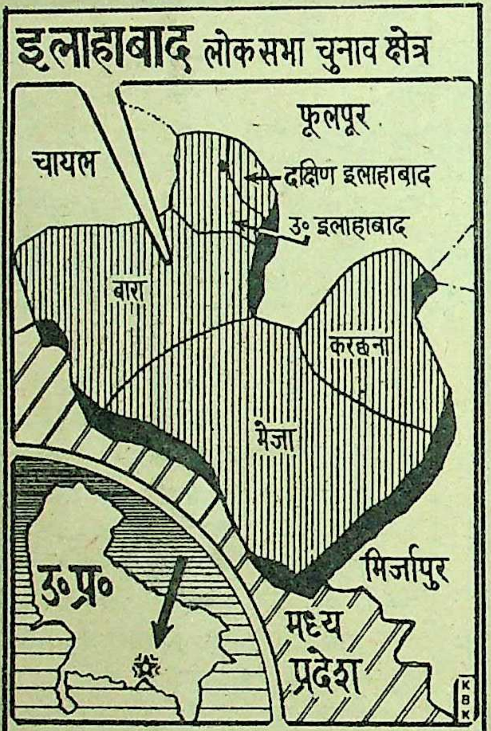

कौन कितने पानी में है? : इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के १९८४ के चुनाव में मतदाताओं की संख्या ७ लाख, ७१ हजार ७३९ थी, जिसमें अब दस प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। इस क्षेत्र में अभी तक हुए दस चुनावों व उपचुनावों में कांग्रेस ८ बार विज रही, १९७४ के उपचुनाव और १९७७ में जनता लहर में हुए आम चुनाव में इस क्षेत्र जनेश्वर मिश्र ने क्रमशः श्रीमती गांधी के वकील एच०सी० खरे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को हराया था। आजादी की लड़ाई में इस शहर ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी, इस शहर ने कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों को विज बनाया, वे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री बने—इस हिसाब से यह क्षेत्र कांग्रे का गढ़ नजर आता है, लेकिन इलाहाबाद के चुनावी इतिहास से पता चलता है कि कांग्रेस कभी भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं रही। पं० जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसी दिग्गज हस्तियों को भी यहां लोहे के चने चबाने पड़ गये थे। १९५२ में पंडित नेहरू तत्कालीन क्षेत्रीय नेता बशीरुद्दीन के मुकाबले मात्र ३१८७१ वोटों से जीते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री की १९५७ और १९६२ की विजय क्रमशः ५६ हजार व ६८ हजार वोटों की थ १९६७ और १९८१ के चुनावों में तो कांग्रे इ के हरिकृष्ण शास्त्री और के०पी० तिवारी तो बमुश्किल १४५४४ और ४६६९१ वोटों अपनी जीत दर्ज करा पाये थे। इससे साफ जाहिर होता है कि इलाहाबाद के मतदाता भेड़-चाल से अपना वोट नहीं डालते।

आचार्य नरेंद्र देव की कर्मभूमि होने के कारण यह क्षेत्र समाजवादियों का प्रभावक्षेत्र माना जाता रहा है। प्रसोपा, भारतीय लोकदल या जनता पार्टी के झण्डे तले लड़े समाजवादी छवि के प्रत्याशियों ने यहां हुए दस चुनावों में दो बार कांग्रेस-इ को हराया और सात बार उसे सीधी टक्कर दी। इस प्रकार समाजवादियों को चाहनेवालों की यह कमी नहीं, तो पहले की जनसंघ और अबकी भाजपा को तरजीह देनेवाले भी इस शहर में कम नहीं हैं। १९६२ के चुनाव में लाल-बहादुर शास्त्री की सीधी टक्कर जनसंघ प्रत्याशी राम गोपाल से थी। १९६७ के चुनाव में जनसंघ प्रत्याशी एच०एल० पाण्डेय ने बीस हजार मत प्राप्त किये थे, तो १९८ में भाजपा के मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद के ३३००८ मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया था। यही वजह है कि कांग्रेस अपनी जीत के प्रति इस बार भी आश्वस्त नहीं है। अमिताभ बच्चन की छवि का इलाहाबाद में आकलन करनेवाले अभी तक भी उनकी जीत के संबंध में कोई निश्चित आकलन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अन्यथा चुनाव तारीख और कांग्रेस-इ प्रत्याशी के रूप में अमिताभ बच्चन की घोषणा हो चुकी होती। १९७७ में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतनेवाले हेमवती नंदन

बहुगुणा विपक्षी प्रत्याशी के रूप में अमिताभ बच्चन से टकरा चुके हैं। हार के बावजूद उन्हें करीब १ लाख मत मिले थे। इतने मतों और अमिताभ बच्चन की स्विस बैंक के खातों में कथित रूप से जमा काले धन के कारण बिगड़ी छवि के बावजूद बहुगुणा भी दावे से अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं, अन्यथा वह भी सीना तानकर अपनी उम्मीदवारी की अभी तक घोषणा कर चुके होते। इस बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की चार पार्टियों (जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स व जनमोर्चा) के संयुक्त मोर्चे ने भी इस उपचुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि लोकदल-ब और जनमोर्चे द्वारा अछूत घोषित भाजपा भी इस उपचुनाव में जोर-आजमाइश का इरादा बना ले। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और विभिन्न हिंदू संप्रदायों के प्रमुखों द्वारा 'हिंदू हितों' की रक्षा करनेवाले को ही वोट देने की अपील करके 'हिंदू वोट बैंक' का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके भरोसे भाजपा को भी अपनी जीत के आसार नजर आ सकते हैं।

जातीय दृष्टि: यहां हुए दस चुनावों में जो भी नेता विजयी हुए, उनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं रहा जो जातिवादी राजनीति करता हो या जो जातिवादी नेता के रूप में मशहूर हो। बहरहाल ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थों का रुख चुनाव परिणामों को प्रभावित करता रहा है। यहां हुए पिछले दस चुनावों में चार बार कायस्थों (लालबहादुर शास्त्री-१९५७ व १९६२, हरिकृष्ण शास्त्री-१९६७ और अमिताभ बच्चन-१९८४), पांच बार ब्राह्मण (पं० नेहरू १९५२, हेमवती नंदन बहुगुणा १९७१, जनेश्वर मिश्र-१९७४ व १९७७ और के०पी० तिवारी-१९८१) तथा एक बार ठाकुर (वी०पी० सिंह-१९८०) ने चुनाव जीता है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या (१२७४८०), हरिजनों (१७८६५०) को छोड़कर अन्य जातियों के मुकाबले (ठाकुर-५२६०४, मुस्लिम-७८०००, यादव-७५३००, कुर्मी एवं अन्य-९४६५०) सर्वाधिक है, इसलिए यदि यह उपचुनाव जातिवाद के आधार पर लड़ा गया, तो छीनाझपटी ब्राह्मण और हरिजन वोटों की होगी। मुस्लिम वोट बैंक यहां के चुनावों में कभी निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाया। जातिवाद के आधार पर होनेवाले चुनावों के अपने खतरे हैं। जहां-जहां जातिवाद को चुनावों में अहमियत मिली, वहां के चुनाव अहिंसक नहीं रह पाये—और उम्मीद करनी चाहिए कि इलाहाबाद के इस उपचुनाव में जातिवादी जहर नहीं घोला जायेगा।

—विनोद मिश्र

और न उनके पिता।

पिछले चुनाव में विद्यार्थियों ने जिस उत्साह से अमिताभ बच्चन का समर्थन किया था, वह अभूतपूर्व था। उस समय विद्यार्थियों ने न केवल अपने स्तर पर प्रचार-द्वार आदि बनवाये थे, बल्कि घरों से निकाल-निकाल कर लोगों से मत भी डलवाये थे। एक विद्यार्थी का कहना था, "हां, जाली मतदान तक करवाया हमने।" लेकिन अब विद्यार्थियों से बात करने पर पता चला कि उनमें वह उत्साह नहीं है। इस समय इलाहाबाद छात्र संघ पर विपक्ष का वर्चस्व है और बाकी छात्र नेता अपने-अपने पार्टी-संबंधों के हिसाब से समर्थन करेंगे। गैरराजनीतिक विद्यार्थी, जिन्होंने अमिताभ की ज्यादा मदद की थी, अब उदासीन दिखायी दे रहे हैं। एन०एस०यू०आई० से संबंधित छात्र-समुदाय का समर्थन उनको मिलेगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस संगठन के एक छात्र का विचार था कि इस समय इस संगठन के अधिकांश लोग राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के प्रभाव में हैं, इसलिए उनके रुख पर ही इस संगठन का समर्थन संभव है।

पिछले चुनाव में अमिताभ बच्चन के चुनावी अभियान के मुख्य कर्ताधर्ता उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन (बंटी) थे। धन की व्यवस्था एवं किन लोगों को क्या करना है, यह कार्य उन्होंने ही किया था। लेकिन इस चुनाव में अमिताभ बच्चन उस कमी को कैसे पूरी करेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। इस समय वह विवादों के घेरे में हैं। यदि वह यहां सक्रिय होते हैं, तो इसका विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन यदि वह नहीं आते हैं, तो उन जैसा विश्वसनीय व्यक्ति उनके पास और कौन है?

स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसियों को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्होंने मूल संगठन को नजरअंदाज किया और 'अमिताभ फैंस क्लब' जैसे संगठन को महत्व दिया। एक वरिष्ठ कांग्रेसी की टिप्पणी थी, "समझ में नहीं आता कि रवि बधावन में अमिताभ बच्चन ने क्या देखा है? यदि वह अपने लिए 'सेकंड लाइन आफ दि फैंस' चाहते थे, तो उन्हें इस ढंग से नहीं करना चाहिए था। जिस संगठन का इलाहाबाद तक में कोई आधार नहीं, उसको आखिर भारतीय नाम देना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपर स्टार के लिए शोभा की बात नहीं।" वरिष्ठ नेताओं का खयाल है कि ऐसे संगठनों में अकसर ऐसे लोग घुस जाते हैं, जो अपने नेता के नाम पर ऐसे काम करते हैं, जिससे उसका नाम होने के बजाय, बदनामी ज्यादा होती है।"

लेकिन फैंस क्लब के समर्थकों का कहना है कि दीवारों पर नारे लिखवा कर, बैनर लगवा कर और तरह-तरह के आयोजन करके अमिताभ बच्चन का नाम 'हमने ही जिंदा रखा है।' लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह 'पैसों के उपयोग के औचित्य को सिद्ध करने के तमाशे हैं।' इन्हीं विरोधियों का कहना है कि आम कांग्रेसियों के बजाय 'फैंस क्लब' के लोग अमिताभ बच्चन को लाने की गुहार इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर पैसे काफी बहने की संभावना नजर आती है।

अमिताभ के लिए ही नहीं कांग्रेस के लिए महेंद्र सिंह टिकैत और डी०एस० फोर भी सिरदर्द है। डी०एस० फोर के नेता कांशीराम की स्थानीय सेंट जोसेफ कालेज में सभाएं हुई हैं, जिनमें भारी मात्रा में हरिजन एकत्र हुए थे। बहुत संभावना है कि इस पार्टी (बहुजन समाज पार्टी) का कोई प्रत्याशी खड़ा हो। यदि ऐसा हुआ, तो कांग्रेस के ३०-४० हजार वोट टूट सकते हैं।

कांग्रेसियों को सबसे बड़ा खतरा इस बात में नजर आ रहा है कि यदि अमिताभ बच्चन फिर से खड़े हुए, तो उनको वे वायदे याद आ जायेंगे, जो उन्होंने चुनाव के समय किये थे। "जिस अनुपात में आशाएं जगायी जाती हैं, निराशा भी उसी अनुपात में होती है", हाई कोर्ट के एक युवा वकील ने कहा। उनका संकेत था कि अमिताभ बच्चन ने आशा जगायी थी कि वह इलाहाबाद को 'रायबरेली-अमेठी' बना देंगे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाने, यमुना नदी पर नया पुल बनवाने और नैनी से मिर्जापुर तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसे अनेक वायदे किये थे, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अमिताभ-समर्थकों का कहना है कि अमिताभ की ओर से निरंतर मेडिकल वैन घूम रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध हो रही है। शहर-विकास के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए दिलवाये हैं। इसी तरह हाई कोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी अमिताभ बच्चन की ही बदौलत भारी-भरकम धनराशि उपलब्ध हुई है। यहां तक कि उन्होंने चुनाव में गोली का शिकार हुए व्यक्ति को जो दस हजार रुपए देने का वायदा किया था, उसे भी उन्होंने पूरा कर दिया।

लेकिन बहुगुणा-समर्थकों का फतवा है कि अमिताभ जीरो के रूप में इलाहाबाद आये थे और जीरो के रूप में उन्हें बेआबरू होकर सीट छोड़नी पड़ी है।

विपक्ष: बहरहाल, अमिताभ के जीतने और हारने का दारोमदार विपक्ष और खासकर वी०पी० सिंह की रणनीति पर निर्भर है। सवाल यह है कि क्या वी०पी० सिंह खुद खड़े होंगे? यदि खुद खड़े नहीं हुए, तो क्या अपने किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे? क्या हेमवती नंदन बहुगुणा ही विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार होंगे?

जैसा कि शुरू में कहा गया है, वीपी

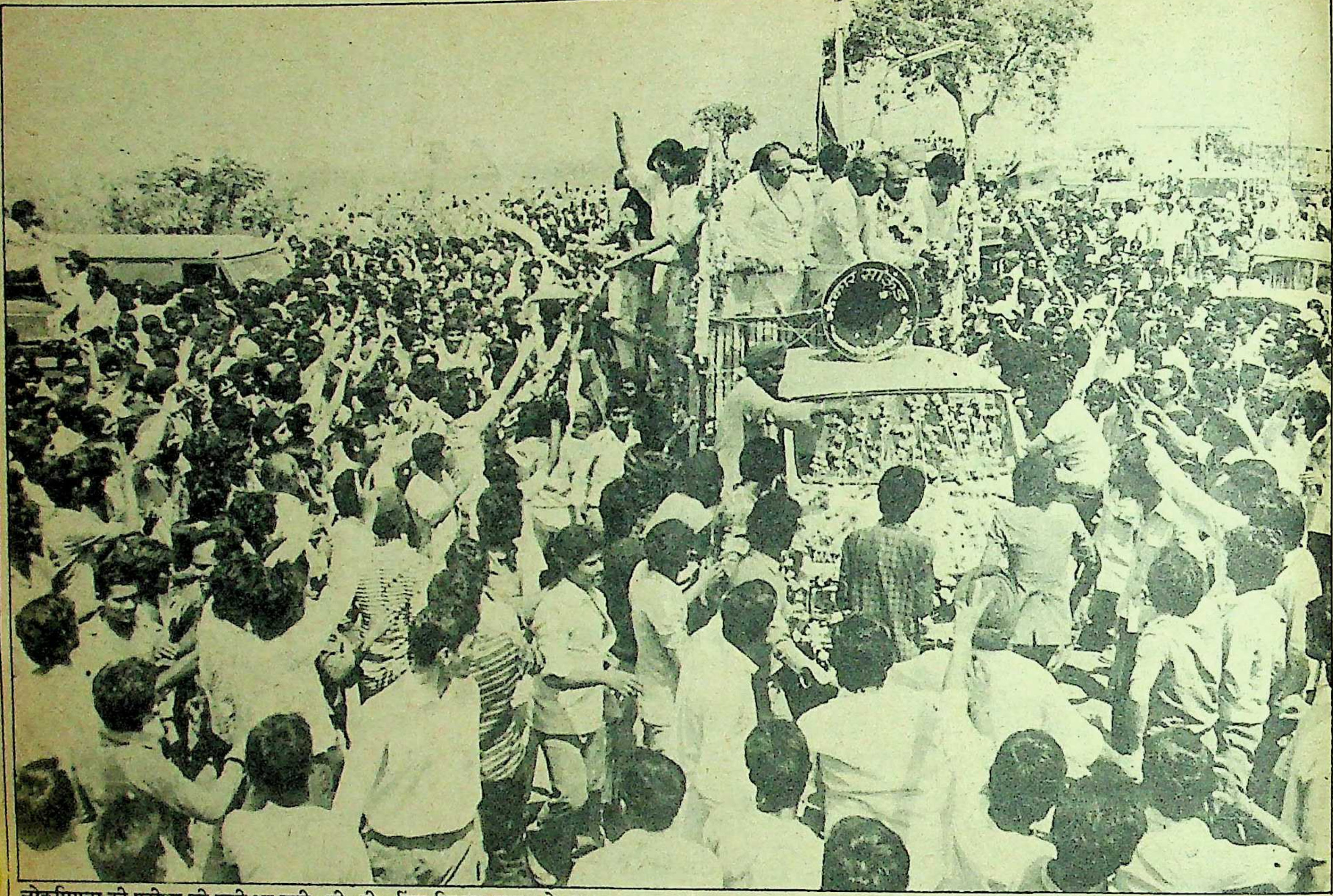

लोकप्रियता की परीक्षा की घड़ी आ गयी : वी०पी० सिह विशाल जुलूस के साथ

सिह का भविष्य इस चुनाव पर टिका है। इलाहाबाद उनका गृहनगर है। सारे देश में वह राजीव गांधी के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। इस समय विपक्ष में वह सबसे ज्यादा भीड़ एकत्र करने वाले नेता बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि वह इस उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाये, तो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर छवि नष्ट होना निश्चित है। जनमोर्चा के अंदरूनी सूत्रों की राय है कि राजा की कोशिश यह होगी कि इस उपचुनाव को वह अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनने दें। लेकिन यदि अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं, तो क्या यह संभव है कि यह चुनाव राजा की प्रतिष्ठा का मुद्दा न बने?

यद्यपि पिछले चुनावों के परिणामों के आधार पर चुनाव हुए, 'तो यह' कैसे संभव है कि यह उनकी आन-वान का सवाल न बने। हालांकि जनमोर्चा के एक वरिष्ठ नेता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "अब हम क्या अपने नेता को नाचने गाने वालों के साथ मैदान में उतारेंगे। लड़ाई बराबर वालों में होती है। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन के कंधे से गोली दागने की कोशिश न करें। हिम्मत हो, तो खुद अखाड़े में आयें। तभी हम विश्वनाथजी को मैदान में उतारेंगे।"

इलाहाबाद लोकसभायी सीट पर राजा मांडा दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। जनता लहर के दौरान १९७७ में वह कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं और १९८० में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वह यहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन पिछले चुनावों के नतीजों के आधार पर अब राजा मांडा के भविष्य का आकलन करना अप्रासंगिक है। अब वह कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस के बागी नेता हैं। इसलिए अब स्थिति बिलकुल उलट गयी है। कल के दुश्मन अब उनके दोस्त हैं और दोस्त दुश्मन हो गये हैं। १९७७ में विश्वनाथ प्रताप सिंह को तत्कालीन भारतीय लोकदल के प्रत्याशी और अब लोकदल-ब के राष्ट्रीय महासचिव जनेश्वर मिश्र ने हराया था, लेकिन अब वह कहते हैं, "विपक्ष को चाहिए कि चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा करे। ऐसी स्थिति में 'जनमोर्चा' नेता वीपी सिंह अथवा लोकदल-ब अध्यक्ष बहुगुणा आसानी से चुनाव निकाल सकते हैं।"

लेकिन क्या राजा के लिए चुनाव जीतना बिलकुल आसान है? इसमें तो कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भ्रष्टाचार-उन्मूलक की छवि बनी है और इसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। स्थानीय महाविद्यालय के एक प्रवक्ता का कहना है, "राजा ने कांग्रेस-इ को अन्याय का और खुद को न्याय का प्रतीक बना लिया है, इसलिए जब भी वह चुनाव में उतरेंगे, जनता अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई मानकर चलेगी।" लेकिन राजनीतिक यथार्थ के पांव इतने लंबे होते हैं कि उनके लिए दार्शनिक धारणाओं की चादर छोटी पड़ जाती है।

राजा को यह मानकर चलना पड़ेगा कि अब सरकारी मशीनरी उनके साथ नहीं है और न सरकार जितने साधन ही उनके पास हैं। फिर यह चुनाव उनकी आन-बान का सवाल होगा, तो मुख्यमंत्री वीर बहादुर के लिए भी जीवन-मरण का प्रश्न होगा। इसलिए वीर बहादुर सिंह उनको या उनके प्रत्याशी को मात देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव-रणनीति का ललकार के साथ जिक्र करते हुए उन्होंने 'माया' को बताया, "मैं एक-एक पोलिंग स्टेशन पर एक-एक विधायक की ड्यूटी लगा दूंगा।"

राष्ट्रीय स्तर पर राजा की छवि कुछ भी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन जब राजा अपने घर के मैदान में उतरेंगे, तो व्यक्तिगत राजनीतिक रागद्वेष कोई भूमिका नहीं निभायेगा, यह नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की

एक मौका और: बहुगुणा जनसभा को संबोधित करते हुए

जो लाबी अमिताभ के खड़े होने पर विरोधी रुख अपना सकती है, वह राजा के खड़े होने पर अमिताभ का साथ देने पर मजबूर हो सकती है, खासकर ब्राह्मण लाबी।

राजनीतिक प्रेक्षकों को राजा के रास्ते में एक बाधा और नजर आती है। वह बाधा है, जातिवाद की। उत्तर प्रदेश में ऐसी बातें आम तौर पर होती हैं कि उनके इर्द-गिर्द उनकी जाति के लोगों का घेरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुल्तानपुर में उनकी विशाल जनसभा हुई थी, लेकिन उसका महत्व घटाने के लिए एक कांग्रेसी नेता ने टिप्पणी की, "जनसभा तो विशाल थी, लेकिन आप उसे जनसभा न कहें, वह क्षत्रिय महासभा थी।" जाहिर है यदि यह धारणा इलाहाबाद के चुनाव के दौरान बनती है, तो बाकी जातियां अपना मुंह मोड़ सकती हैं। शायद इसीलिए एक युवा विपक्षी नेता ने कहा, "वीपी का जीतना चाहे भले संदिग्ध हो, लेकिन उनमें किसी को जिताने की अपार क्षमता है।"

यदि अमिताभ बच्चन के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद में करने के लिए तो बहुत कहा, लेकिन असलियत में किया कुछ नहीं, तो राजा के लिए भी यह कहा जाता है कि वह इतने ऊंचे पदों पर रहे, लेकिन इलाहाबाद के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गिनाया जा सके। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इलाहाबाद के प्रति उनकी उदासीनता इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभायेगी। वीपी सिंह विपक्ष के अन्य दलों से समीकरण बिठाने के मामले में, जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति में हैं, उस पर नजर दौड़ायी जाये, तो यह नहीं लगता कि इस ऊहापोह का यहां विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अभी तक उन्होंने जनमोर्चा से लोकदल-अ, कांग्रेस-स और जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। वह भाजपा से अपने को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी वामपंथी छवि बना रहे हैं, लेकिन भाजपा से बिना तालमेल किये वह इलाहाबाद में काम नहीं चला सकते। स्वयं उनके जनमोर्चा के नेता—खासकर आरिफ मोहम्मद खान-चाहते हैं कि भाजपा से तालमेल बिठाया जाये। वामपंथी दलों से उनके संबंध बनाने के विचार से जनमोर्चा के संयोजक रामधन सहमत नहीं लगते। उनकी राय में हिंदीभाषी क्षेत्र में वामपंथी दलों का कोई महत्व नहीं है। अतः इलाहाबाद चुनाव में भाजपा को नजरअंदाज करके वह काम नहीं चला सकते। हालांकि इलाहाबाद से कभी जनसंघ या भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता है, लेकिन शहर में भाजपा के २०-२५ हजार प्रतिबद्ध वोट हैं।

बहुगुणा: यदि वीपी सिंह नहीं खड़े होते हैं, जैसा कि लगता है—और यदि भूरेलाल या अपने अन्य प्रत्याशी को नहीं खड़ा करते हैं, तो क्या हेमवती नंदन बहुगुणा ही विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार होंगे? पिछले चुनाव में अमिताभ के सामने बहुगुणा ही प्रत्याशी थे। लेकिन पिछले दफा सहानुभूति-लहर और अमिताभ के ग्लैमर के सामने उनका अनुभव, उनकी वरिष्ठता, इलाहाबाद के लिए किये गये कार्य कारगर नहीं हो सके। यों १९७१ में बहुगुणा इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन बहुगुणा के करीबी लोगों का कहना है कि वह उप चुनाव लड़ने के लिए बहुत लालायित नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि बहुगुणाजी सिद्धांततः यह मानते हैं कि इलाहाबाद की जनता ने उनको पांच साल के लिए हराया है, इसलिए वह उपचुनाव में खड़े होकर एक-डेढ़ साल के लिए यहां का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक नहीं हैं।

लेकिन विपक्ष उनको सर्वसम्मत प्रत्याशी बनाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि वह इनकार

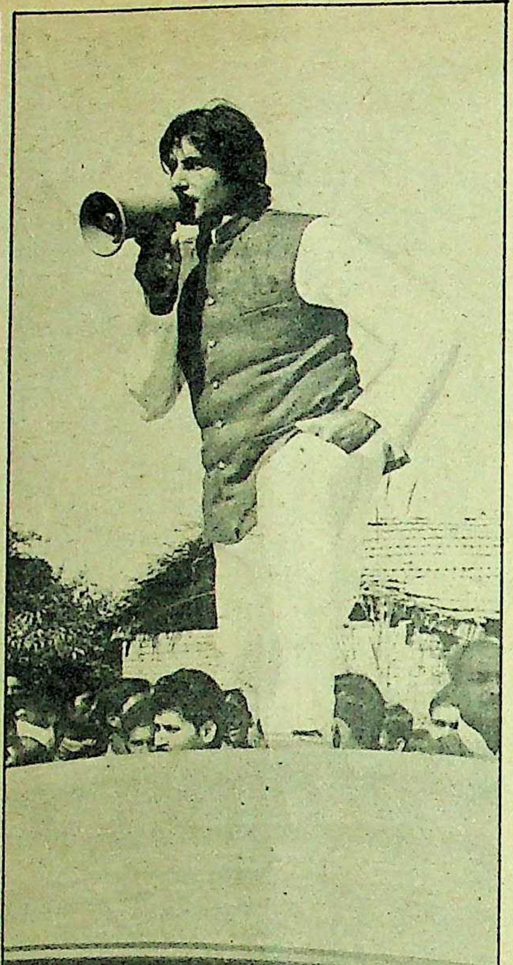

अब किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? अमिताभ पिछले चुनाव के दौरान

> **यों तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में काफी समय से इलाहाबाद की दीवारें रंगी जा रही हैं, भूख हड़ताल हो रही है, ज्ञापन दिये जा रहे हैं, लेकिन जब से वह लक्षद्वीप में राजीव गांधी के साथ नव वर्ष मना कर लौटे हैं, तब से लगभग यह माना जा रहा है कि इलाहाबाद से वही प्रत्याशी होंगे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनके नाम की घोषणा के पहले बोफोर्स की रिपोर्ट पेश की जायेगी, जिसमें उनका निर्दोष साबित होना निश्चित माना जा रहा है। इस बीच उनकी 'शहंशाह' फिल्म भी धूम मचा चुकेगी। इसके बाद वह यह आह्वान करते हुए चुनाव मैदान में कूदेंगे कि हिम्मत हो, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह मुझसे चुनाव लड़ें।**

कर पायेंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि पिछली दफा की बात तो और थी, लेकिन इस बार बात और है। यदि राजीव गांधी और अमिताभ की बोफोर्स से नष्ट हुई छवि को भी जानें, तो भी इस बार इलाहाबाद की जनता बहुगुणा के वे काम नहीं भूलेगी, जो उन्होंने इलाहाबाद के लिए किये हैं। इन समर्थकों की राय में आजादी के बाद इलाहाबाद के विकास की नींव बहुगुणा ने ही डाली थी। १९५२ में करछना से विधायक चुने गये थे, जिसमें बारा-मेजा का क्षेत्र भी समाहित था। उस समय उन्होंने बिजली और पानी उपलब्ध कराने के लिए जो कार्य किया, उसे कोई नहीं भुला सकता। पंडवापुर-परतापपुर कैनाल उन्हीं की देन मानी जाती है, जिसने इस क्षेत्र का कायापलट किया है। संचारमंत्री के रूप में उन्होंने टेलीफोन उद्योग की नींव डाली, वीपीसीएल, टीएसएल और इफ्को जैसे उद्योगों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इन उद्योगों में करछना और मेजा के लोगों को जो रोजगार मुहैया करवाया गया, उसके कारण यहां के लोग उनसे उपकृत महसूस करते हैं। अध्यापकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के कल्याण-कार्यों का श्रेय भी बहुगुणा को है। जाहिर है इन कार्यों का इस चुनाव में वास्ता दिया जायेगा।

यदि चुनाव में जातिवाद ने गुल खिलाया, तो भी बहुगुणा फायदे में रहेंगे। फिर मुस्लिमों का कांग्रेस के प्रति मोहभंग हुआ है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मसले ने इस मोहभंग को और बढ़ाया है। बहुगुणा के प्रति मुस्लिम मतदाताओं का रुझान पहले से ही रहा है, ऐसी स्थिति में उनको इस वर्ग का समर्थन मिलने की आशा है। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के रुख का पता एक बुजुर्ग कलाकार की इस टिप्पणी से मिलता है, "जब-जब कांग्रेस की कुरसी खतरे में होती है, वह हमारी जिंदगी खतरे में डालने के लिए सांप्रदायिकता को हवा देती है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।"

लेकिन यहां इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि चाहे कांग्रेस से मुसलमान नाराज हों, लेकिन अमिताभ के प्रति इस वर्ग के लोगों में अब भी लगाव है—खासकर महिलाओं और नौजवानों में। विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार बनने के लिए बहुगुणा की स्थिति अवश्य मजबूत हो जाती है। फिर लोकदल-ब के वह अध्यक्ष हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के मत उन्हें मिलेंगे। बहुगुणा के कुछ अंध समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि अब इलाहाबाद से उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। जमरा के ब्लाकप्रमुख महादेव गुप्त एवं मेजा के ब्लाकप्रमुख त्रिवेणी प्रसाद इसी मत के हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बाधा है उनका इलाहाबाद से १०-१२ साल दूर रहना। उनके इलाहाबाद में न रहने से उनके कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का कोई पुछत्तर नहीं रहा। इससे उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ है। फिर वह चाहे सर्वसम्मत उम्मीदवार ही क्यों न हों और चाहे हरियाणा में भाजपा के साथ उनका गठबंधन ही क्यों न हो, लेकिन यह माना जाता है कि भाजपा के वोट उनको कतई नहीं मिलेंगे—चाहे इस पार्टी को अपना मत कांग्रेस को ही क्यों न देना पड़े?

लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव-अप्रभाव से ज्यादा इस चुनाव को विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दे की ओर मोड़ने का भरपूर प्रयास करेगा। जैसा कि लग रहा है, विपक्ष इस चुनाव को 'राष्ट्रीय मर्यादा' का सवाल बनायेगा और इसी पर जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करेगा और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होती है।

अमिताभ का विरोध: इसीलिए २ फरवरी को जब इलाहाबाद के नेता गुलाम नबी आजाद से मिले, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अमिताभ बच्चन को न खड़ा किया जाये। इस मीटिंग के बाद से प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों में काफी परेशानी पैदा हो गयी है। अभी तक अधिकांश कांग्रेसी बच्चन को इलाहाबाद से खड़ा करने के खिलाफ थे, लेकिन खुलकर किसी ने विरोध नहीं किया था। मगर अब काफी कांग्रेसी आपस में मिलकर इस परामर्श में लग गये हैं कि किस तरकीब से राजीव गांधी को समझाया जाये कि बच्चन पर कांग्रेस को दांव पर लगाना घातक होगा। एक पार्टी पूर्व महासचिव का कहना था कि अगर बच्चन को फिर से खड़ा किया, तो जनता को यही संदेह होगा कि सारी पार्टी बच्चन के किये—अनकिये को अपने सिर-माथे पर लेती है। इसका अर्थ है कि अजिताभ पर स्विट्जरलैंड धन ले जाने का जो कुछ भी आरोप लगा है, उसमें हम सब शरीक हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी इस बात से ज्यादा क्षुब्ध हैं कि लक्षद्वीप में बैठकर अपने आप अमिताभ बच्चन को प्रत्याशी बनाने का निर्णय ले लिया। फिर अमिताभ बच्चन पारंपरिक कांग्रेसी भी नहीं, वह मात्र प्रधानमंत्री के दोस्त हैं जबकि अमिताभ हारते हैं, तो वह निर्णय कांग्रेस और उसके एकछत्र नेता राजीव के खिलाफ जनादेश समझा जायेगा। कमलापति त्रिपाठी और उमाशंकर दीक्षित इसी मत के माने जाते हैं। इनके नजदीकी माने जाने वाले व्यक्ति का कहना था कि अगर सुनील शास्त्री खड़े होने से इनकार करते हैं, तो उड़ीसा के राज्यपाल बी०एन० पांडे को खड़ा कर दिया जाये। पांडे का अपना युवा काल इलाहाबाद और वहां की राजनीति में गुजरा है। वह शहर के मेयर भी रहे हैं। 'भारत में अंग्रेजी राज' जैसी प्रख्यात पुस्तक के वह रचयिता हैं, जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित की थी। दिवंगत कांग्रेसी नेता सुंदर लाल के साथी होने के कारण उनका इलाहाबाद

में काफी सम्मान है। वह ब्राह्मण वोट भी ज्यादा विभाजित नहीं होने देंगे। यह भी उम्मीद की जा सकती है कि चौधरी नौनिहाल सिंह आदि के कारण कायस्थ वोट पांडेजी को मिल सकते हैं।

कांग्रेसियों की राय प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री के पक्ष में इसलिए है कि शास्त्री परिवार वीपी सिंह के काफी निकट है। सुनील शास्त्री आदि उन्हें मामा कह कर पुकारते हैं। ऐसी स्थिति में उनके खड़े होने पर चुनाव में गंदगी नहीं उछलेगी।

उन्होंने ऐसी तैयारी भी शुरू कर दी है। यह भी कहा जाता है कि कुछ वरिष्ठ अफसरों की तैनाती और तबादला बच्चन को मद्देनजर रख कर किया जा रहा है। केंद्र में भी ऐसा हो रहा है। हाल में पी०पी० श्रीवास्तव की केंद्रीय गृह मंत्रालय में नियुक्ति को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है।

लेकिन सत्तारूढ़ दल की सारी शक्ति यदि इस उपचुनाव पर लगती है, तो सारे विपक्ष की शक्ति का भी यहां केंद्रित होना सुनिश्चित है। कहा जाता है कि अभी जब एन०टी० रामाराव गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक के सिलसिले में दिल्ली आये थे, तो उनसे कहा गया कि अपने प्रख्यात 'चैतन्य रथ' के साथ वह इलाहाबाद आयें। होली के करीब 'जनमोर्चा' के नेता इलाहाबाद में पड़ाव डालने वाले हैं। कहा जाता है कि १९८४ में उत्साही नवयुवकों ने ५०-५० जाली मत डाले थे। इसलिए विपक्ष चुनाव को राष्ट्रीय मोड़ देने और जाली मतदान रोकने के लिए देश के युवकों और किसानों से अपील करने की सोच रहा है कि वे इलाहाबाद में लामबंद होकर देश की मर्यादा की रक्षा करें। इसी कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य विपक्षी नेता महाराष्ट्र के शरद जोशी और पश्चिमी उ०प्र० के टिकैत से संपर्क कर रहे हैं। इलाहाबाद की युवा शक्ति, जिस पर बच्चन की उम्मीद टिकी है, पर दबाव डालने के लिए देश के अन्य भागों से नौजवानों को लाने की कोशिश की जा रही है। एक लाख युवक और किसान इलाहाबाद में आकर मतदान में संभावित हेराफेरी को रोकेंगे, ऐसी योजनाएं बन रही हैं।

ऐसी स्थिति में यह उपचुनाव ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। 'संगम' किस को पवित्र घोषित करता है और किसकी इज्जत विसर्जित करता है, इसका पता इस चुनाव में लगेगा।

अफवाह गर्म है कि 'रामायण' सीरियल के 'राम' अरुण गोविल को अमिताभ बच्चन के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ताकि 'रावण' को पराजित किया जा सके। बहरहाल, यह तो वक्त बतायेगा कि इस चुनाव में रावण कौन है और राम कौन है ?

—'माया' सर्वे टीम,
लखनऊ ब्यूरो, दिल्ली ब्यूरो

प्रेमशंकर झा का नजरिया

इलाहाबाद उपचुनाव का महत्व

प्रेम शंकर झा : 'हिंदुस्तान टाइम्स' के पूर्व संपादक, देश के विख्यात अर्थ विशेषज्ञ व राजनीतिक समीक्षक

इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। नवजात 'जनमोर्चा' के भविष्य का निर्धारण इसी चुनाव के द्वारा होगा। देखा जाये तो जनमोर्चा के लिए यह जीवन-मरण के प्रश्न जैसा है। यदि जनमोर्चा यह चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो समूचे उत्तर प्रदेश में भविष्य में विकल्प की हैसियत पा लेगा। राजीव गांधी और वी०पी० सिंह के बीच की दरार और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री पर लगे आरोपों के कारण हिंदी प्रदेशों के निराश-त्रस्त कार्यकर्ता इलाहाबाद उपचुनाव में अपना भविष्य देखेंगे। चुनाव परिणाम के आधार पर ही वह तय करेंगे कि उन्हें किस पाले में रहना है। लेकिन यदि मोर्चा समर्थित उम्मीदवार हार जाता है, तो कांग्रेस के विकल्प के रूप में इसकी विश्वसनीयता फिलहाल समाप्त हो जायेगी। दोनों पार्टियों के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा के समान है, लेकिन हारने पर कांग्रेस की अपेक्षा जनमोर्चा को ज्यादा क्षति हो सकती है। लंबे इतिहास और बेहतर संगठन की बदौलत कांग्रेस आगे भी लड़ाई जारी रख सकती है, जबकि जनमोर्चा के लिए यह आखिरी मौका होगा।

कांग्रेस चुनाव को क्यों टाल रही है, यह समझना मुश्किल है। कांग्रेस संगठन के प्रमुख यह मानते हैं कि अमिताभ बच्चन सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर संसद से तुरंत इस्तीफा देने के कारण उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी है। अनुशासन और निःस्वार्थ भावनाओं की मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं और मतदाता इसे अनदेखा नहीं करेंगे। यदि अजिताभ के विदेशी सौदों और बोफोर्स सौदे की जांच कर रही संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट आने तक चुनाव नहीं होते और बच्चन बंधु साफ बरी हो जाते हैं, तो अमिताभ के लिए इलाहाबाद की सीट दोबारा जीतने के बढ़िया अवसर हैं।

जनमोर्चा को इस सबसे सावधान रहना चाहिए। मोर्चे के नेताओं को जानना चाहिए कि उनके पास केवल दो रास्ते हैं। यदि पूर्व घोषणा के अनुसार अमिताभ खड़े होते हैं, तो वह भी कोई तगड़ा उम्मीदवार खड़ा करे या फिर चुनाव का बहिष्कार करे। मजबूत उम्मीदवार निश्चित रूप से खुद वीपी सिंह हैं। खास तौर पर इलाहाबाद के लिए, क्योंकि वह उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है, लेकिन उनके खड़े होने का मतलब है जनमोर्चा को बहुत बड़े खतरे में डालना। 'माया' द्वारा कराये गये जनमत सर्वेक्षण से, यद्यपि इसका आधार छोटा था, अमिताभ को इलाहाबाद में भारी समर्थन मिलता दिखलायी देता है। अतः वीपी सिंह के लिए भी यह एक कठिन चुनौती हो सकती है।

इसके बावजूद जनमोर्चा के पास वास्तव में कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। यदि वह चुनाव में भाग नहीं लेता, तो लोग इसका यही मतलब निकालेंगे कि उसके पास समर्थन और आत्मविश्वास नहीं है। बहिष्कार के निर्णय से लोगों को लगेगा कि वीपी सिंह अनिर्णय से ग्रस्त हैं और अपने सकल्प को साकार करने का साहस उनमें नहीं है। उनके हाल के अभियान को भी 'बदले की भावना' से संचालित समझा जायेगा। लेकिन जो लोग वीपी सिंह से मिले हैं और जिन्होंने वित्तमंत्री के रूप में उनको देखा है, वह जानते हैं कि यह सच नहीं है। चुनाव की घोषणा के बाद इस चुनौती से वह मुंह नहीं मोड़ सकते।

यदि जनमोर्चा यह चुनौती स्वीकार कर लेता है, तो इससे उसे संगठन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। अभी उसे निचले स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए लोकदल-अ, जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा करना पड़ता है। यह मुश्किल चुनाव तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर काम करने के लिए दबाव डाल सकता है। यह विपक्ष के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। मृतप्राय राजनीतिक संगठनों को गतिशील बनाने के लिए उसकी जरूरत भी है। वीपी सिंह कहते रहे हैं कि जनमोर्चा अराजनीतिक हैं और आगामी उपचुनावों में वह कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अभियान के शुरुआत में उन्होंने किसी पार्टी से करीबी रिश्ते नहीं बनाये, जिससे जनमोर्चा की छवि साफ-सुथरी बनी रही। सिंह इससे वाकिफ थे इसीलिए उन्होंने मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। उनको इस नीति का फायदा मिला और उत्तर प्रदेश तथा अन्य उत्तरी क्षेत्रों में उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन जनमोर्चा के लिए जड़ जमाने का समय अब आ गया है।

■

माया सर्वेक्षण

इलाहाबाद उपचुनाव

हारेगा कौन ?

'माया' की सर्वे टीम ने इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ८५६ ग्रामीणों और शहरियों से ग्यारह लिखित प्रश्नों पर लिखित राय ली। यह सर्वे टीम इस निर्वाचन क्षेत्र के न केवल शहरी इलाकों में, बल्कि दूरदराज के गांवों में हर तबके के लोगों तक पहुंची। जिन लोगों की राय ली गयी, उनमें प्रायः सभी जाति व वर्ग के लोग शामिल थे जो खेती, मजदूरी, नौकरी, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, वकालत, शिक्षण आदि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। यहां प्रस्तुत हैं, सर्वेक्षण के निष्कर्ष :

कोई अप्रत्याशित अड़चन नहीं आयी, तो इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव हाई स्कूल-इंटर की परीक्षाओं के बाद अप्रैल या मई में संभावित हैं। अभी प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए इस उपचुनाव के संबंध में अभी से कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, फिर भी ऐन उपचुनाव के मौके पर मतदाताओं का रुख पलट देनेवाली कोई धमाकेदार घटना नहीं हुई, तो 'माया' का यह सर्वेक्षण अनेक मायनों में दिशा-निर्देशक सर्वेक्षण साबित हो सकता है।

माया द्वारा किये गये सर्वेक्षण के कई निष्कर्ष तो बेहद चौंकानेवाले हैं। अपने भाई अजिताभ बच्चन के कारण अमिताभ बच्चन की राजनीतिक क्षेत्र में बदनामी के बावजूद इलाहाबाद के मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। फिल्मी परदे का सुपर स्टार अमिताभ अभी भी बहुसंख्यक मतदाताओं के दिलों में बसा हुआ है। दूसरी ओर केंद्र में राजीव गांधी को सीधी टक्कर देने के लिए ताकत बटोरने में लगे विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने गृहनगर इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमिताभ से कम प्रभावशाली हैं। 'माया' ने जिन ८५६ मतदाताओं की राय ली है, उनमें से यद्यपि ४१.३५ प्रतिशत मतदाताओं ने वी०पी० सिंह को ईमानदार घोषित किया है, फिर भी सिर्फ २४ प्रतिशत मतदाता उन्हें बेहतर प्रत्याशी मानते हैं और यदि वह चुनाव में खड़े हुए, तो करीब २५ प्रतिशत मतदाताओं ने ही उन्हें समर्थन देने की बात कही है। दूसरी ओर ८५ प्रतिशत मतदाताओं को अमिताभ के इस्तीफे की जानकारी है और ५४ प्रतिशत मतदाता उनके इस्तीफे के कारणों से भी परिचित हैं, ५९ प्रतिशत बोफोर्स-प्रकरण को भी जानते हैं तथा ६२ प्रतिशत उनके इस्तीफे को उचित भी नहीं मानते, फिर भी ५८ प्रतिशत मतदाताओं का कहना है कि वे अमिताभ बच्चन का फिर से चुनाव लड़ना उचित मानते हैं। ६३ प्रतिशत मतदाताओं की राय में अमिताभ ने अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किये और उन्हें बेहतर प्रत्याशी माननेवालों की संख्या सिर्फ ३९ प्रतिशत है एवं सिर्फ ३० प्रतिशत मतदाता उन्हें ईमानदार मानते है तथापि ५०.३५ प्रतिशत मतदाताओं ने कहा है कि यदि अमिताभ बच्चन चुनाव में खड़े होते हैं, तो वे उन्हे समर्थन देंगे।

बहरहाल, अमिताभ बच्चन की उपचुनाव में विजय कोई आसान खेल साबित नहीं होगी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में अल्प ही सही, लेकिन कमी आयी है। माया सर्वेक्षण की परिधि में आये लोगों में से १९८४ में जहां ६९ प्रतिशत मतदाताओं ने उन्हें अपना वोट दिया था, वहीं अब उन्हें वोट देने का वायदा करनेवालों की संख्या घटकर पचास प्रतिशत रह गयी है। दूसरी ओर यदि विपक्ष ने अपना संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया, तो वी०पी० सिंह व बहुगुणा को वोट देने का वायदा करनेवाले क्रमश: २५ प्रतिशत और २३ प्रतिशत मतदाताओं की मिलीजुली ताकत अमिताभ को कड़ी टक्कर दे सकती है, वैसे भी बहुगुणा व वी०पी० सिंह को बेहतर प्रत्याशी माननेवाले क्रमशः २३ व २४ प्रतिशत मतदाता मिलकर अमिताभ को बेहतर प्रत्याशी माननेवाले ३९ प्रतिशत मतदाताओं पर भारी पड़ जाते हैं।

१९८४ के चुनाव में युवकों और युवतियों के वोटों को अमिताभ बच्चन के फिल्मी ग्लैमर ने अपनी झोली में डाल लिया था, लेकिन उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के फलस्वरूप चली सहानुभूति लहर ने भी वोट दिलवाये थे। अब ऐसी कोई लहर नहीं है, अत: ये वोट इस बार अमिताभ बच्चन के विरुद्ध भी जा सकते हैं। १९८४ के चुनाव में उन महिलाओं ने भी मतदान किया था, जो अकसर चुनावों में वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलतीं। ये महिला मतदाता अमिताभ समर्थक थीं और अभी भी उनमें अमिताभ के प्रति सहानुभूति-समर्थन बरकरार है।

अमिताभ बच्चन के समर्थन में जहां १९ प्रतिशत की कमी आयी है, वहां बहुगुणा के समर्थक मतदाताओं में केवल चार प्रतिशत की कमी आयी है, फिर भी कहा जा सकता है कि २० प्रतिशत मतदाता उनके प्रतिबद्ध मतदाता हैं। ८५६ लोगों में से १९८४ के चुनाव में २७ प्रतिशत मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, जबकि उन्हें वोट देने का वायदा करनेवालों और उन्हें बेहतर प्रत्याशी माननेवालों का प्रतिशत क्रमश: २३ और २३ है। यदि संयुक्त विपक्ष बहुगुणा को अपना प्रत्याशी बनाता है और विपक्ष के वोट बंटने या कटने नहीं पाते हैं, तो बहुगुणा इस बार अमिताभ बच्चन को १९८४ से भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

'माया' सर्वेक्षण का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी मुसलमानों पर तो बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि विवाद तथा मेरठ दंगों का कुछ असर पड़ा है, लेकिन देहाती क्षेत्र के मुसलमान इससे अप्रभावित हैं। सर्वे के तहत १९८४ के चुनाव में ६७ प्रतिशत मुस्लिमों ने अमिताभ को वोट दिये थे और ५७ प्रतिशत मुसलमानों ने उपचुनाव में वोट देने का वायदा किया है। अमिताभ विमुख ये दस प्रतिशत मुस्लिम मतदाता मुख्यत: शहरी हैं और वे वी०पी० सिंह समर्थक बन गये हैं, जबकि बहुगुणा समर्थक मुस्लिम मतदाता बहुगुणा के समर्थन में अडिग हैं। १९८४ के चुनाव में ३३ प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने बहुगुणा को वोट दिये थे और आगामी उपचुनाव में वोट देने का वायदा करनेवाले मुस्लिम मतदाताओं का

कौन अधिक ईमानदार ?

जातीय स्थिति	कुल संख्या	राजीव	वी०पी० सिंह	अमिताभ	कोई नहीं
हरिजन	२१२	३८	७५	८५	१४
वैश्य	१४०	३४	६६	३७	३
ठाकुर	६६	९	४७	१०	—
ब्राह्मण	२२८	८३	९०	४६	९
मुस्लिम	११३	२३	३९	४३	८
कायस्थ एवं अन्य	९७	१५	३७	३८	७
योग	८५६	२०२	३५४	२५९	४१
प्रतिशत		२३.५९	४१.३५	३०.२५	

प्रतिशत भी ३३ ही है।

यहां प्रस्तुत हैं, प्रश्नानुसार सर्वेक्षण के परिणाम :

प्रश्न—१ : १९८४ में किसे वोट दिया ?

'माया' सर्वेक्षण के अनुसार ८५६ मतदाताओं में से ५९२ अर्थात ६९ प्रतिशत मतदाताओं ने अमिताभ बच्चन को तथा २३५ अर्थात २७ प्रतिशत मतदाताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को वोट दिये थे। जातीय हिसाब से मतों का विश्लेषण करने से यह दिलचस्प निष्कर्ष निकलता है कि इलाहाबाद के मतदाता जातीय दृष्टिकोण नहीं रखते। जातीय आधार पर मतदाताओं को गिरोहबंद करने की कोशिशें यदि की भी गयी हों, तो उनका मतदाताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बड़ा शोर था कि मुस्लिम-ब्राह्मण वोट बहुगुणा की झोली में गिरे थे, लेकिन 'माया' सर्वेक्षण से पता चलता है कि २२८ ब्राह्मणों और ११३ मुस्लिमों में से क्रमश: १६४ और ७६ वोट अमिताभ बच्चन को मिले थे और ऐसा नही कहा जा सकता कि किसी ने जातीय आधार पर बहुगुणा या अमिताभ के समर्थन में अपना मत दिया।

प्रश्न—२ : क्या अमिताभ के इस्तीफे की जानकारी है ?

'माया' टीम ने जिन ८५६ लोगों की राय ली, उनमें से ७२५ अर्थात ८५ प्रतिशत लोगों को अमिताभ के इस्तीफे की जानकारी है। करीब शत-प्रतिशत शहरी मतदाता इसके जानकार हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के खासकर पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते कि अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया है। २१२ हरिजनों में से ६७ हरिजनों को अमिताभ के इस्तीफे की जानकारी नहीं है।

प्रश्न—३ : क्या अमिताभ के इस्तीफे का कारण पता है ?

८५६ लोगों में से सिर्फ ४६६ अर्थात ५४.४३ लोगों ने बताया कि वे अमिताभ के इस्तीफे के कारणों से परिचित हैं। शेष ३९० लोगों को अमिताभ के इस्तीफे के कारणों की जानकारी नहीं है। २१२ हरिजनों में १४१ और ७५ वैश्यों में ६५ को नही पता कि अमिताभ ने इस्तीफा क्यों दिया था ?

प्रश्न—४ : क्या अमिताभ का इस्तीफा उचित था ?

८५६ लोगों में से ५३० अर्थात करीब ६२ प्रतिशत लोग अमिताभ के इस्तीफे को उचित नहीं मानते।

प्रश्न—५ : क्या अमिताभ का फिर चुनाव लड़ना उचित है ?

८५६ लोगों में से ४९४ लोगों की राय में अमिताभ का फिर से चुनाव लड़ना उचित नहीं है।

प्रश्न—६ : किसे वोट देंगे ?

'माया' सर्वेक्षण के अनुसार यदि चुनाव में अमिताभ, वी॰पी॰ सिंह व बहुगुणा चुनाव लड़ते हैं, तो ८५६ मतदाताओं में से ४३१ अर्थात ५०.३५ प्रतिशत अमिताभ को, २३३ अर्थात २४.८८ प्रतिशत वी॰पी॰ सिंह को और १९४ अर्थात २२.६६ प्रतिशत मतदाता बहुगुणा को मत देंगे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि न केवल अमिताभ को पिछले चुनावों की अपेक्षा अपना समर्थन देनेवालों की संख्या में कमी आयी है, बल्कि बहुगुणा के समर्थक भी घटे हैं और पिछले चुनावों के बहुत से अमिताभ व बहुगुणा समर्थक अब वी॰पी॰ सिंह के खेमे में चले गये हैं। यदि अमिताभ चुनाव में खड़े होते हैं और विपक्षी संयुक्त टक्कर देते हैं, तो अमिताभ के लिए यह चुनाव जीतना आसान नहीं रह जायेगा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मतदाता वी॰पी॰ सिंह को तो वोट देने को तैयार हैं, लेकिन यदि श्री सिंह अपने किसी प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं, तो मतदाता शायद ही उन्हें वोट दें।

अमिताभ के वायदे

जातीय स्थिति	कुल संख्या	क्या अमिताभ ने वायदे पूरे किये ?	
		हां	नहीं
हरिजन	२१२	६५	१४७
वैश्य	१४०	३४	१०६
ठाकुर	६६	२७	३९
ब्राह्मण	२२८	१०५	१२३
मुस्लिम	११३	४०	७३
कायस्थ एवं अन्य	९७	४३	५४
योग	८५६	३१४	५४२
प्रतिशत		३६.६८	६३.३२

अमिताभ : मतदाता कितना जानते हैं ?

जातीय स्थिति	कुल संख्या	क्या बोफोर्स का नाम सुना है ?		क्या अमिताभ के इस्तीफे की जानकारी है ?		क्या अमिताभ के इस्तीफे का कारण पता है ?	
		हां	नही	हां	नहीं	हां	नहीं
हरिजन	२१२	६८	१४४	१४५	६७	७१	१४१
वैश्य	१४०	१०६	३४	१२४	१६	७५	६५
ठाकुर	६६	५३	१३	६३	३	४८	१८
ब्राह्मण	२२८	१३९	८९	२०७	२१	१३३	९५
मुस्लिम	११३	५५	५८	१०९	४	५९	५४
कायस्थ एवं अन्य	९७	८६	११	७७	२०	८०	१७
योग	८५६	५०७	३४९	७२५	१३१	४६६	३९०
प्रतिशत		५९.२२	४०.७८	८५	१५	५४.४३	४५.६७

प्रश्न—७ : क्या भूरेलाल को जानते हैं ?

८५६ मतदाताओं में से ५५४ लोगों अर्थात ६४.७१ प्रतिशत ने भूरेलाल का नाम सुना है। अधिकांश शहरी मतदाता उनके नाम से

बेहतर प्रत्याशी कौन ?

जातीय स्थिति	कुल संख्या	वी०पी० सिंह	अमिताभ	भूरेलाल	एन०डी० तिवारी	बहुगुणा	सोनिया
हरिजन	२१२	४६	९२	X	४	३९	३१
वैश्य	१४०	३४	५६	४	२	३४	१०
ठाकुर	६६	३०	१३	६	४	१०	३
ब्राह्मण	२२८	५१	८०	१६	२	४८	३१
मुस्लिम	११३	२०	४८	४	१	३८	२
कायस्थ	९७	२५	४२	१	२	२४	३
योग	८५६	२०६	३३१	३१	१५	१९३	८०
प्रतिशत		२४.०६	३८.६६	३.६७	१.७५	२२.५४	९.३४

भूरेलाल की स्थिति

जातीय स्थिति	कुल संख्या	भूरेलाल को जानते हैं ?	
		हां	नहीं
हरिजन	२१२	१०४	१०८
वैश्य	१४०	९१	४९
ठाकुर	६६	४९	१७
ब्राह्मण	२२८	१६०	६८
मुस्लिम	११३	६९	४४
कायस्थ एवं अन्य	९७	८१	१६
योग	८५६	५५४	३०२
प्रतिशत		६४.७१	३५.२९

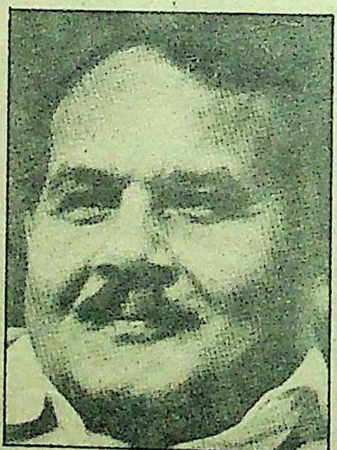

परिचित हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के खेती-किसानी में लगे और पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके काम तक की जानकारी नहीं है।

प्रश्न—८ : क्या अमिताभ ने अपने वायदे पूरे किये ?

८५६ मतदाताओं में से करीब ६३ प्रतिशत मतदाता ऐसा नहीं मानते कि अमिताभ ने अपने चुनावी वायदे पूरे किये हैं। सिर्फ ३७ प्रतिशत मतदाता ही ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि अमिताभ ने अपने चुनावी वायदों को पूरा किया है।

प्रश्न—९ : क्या बोफोर्स को जानते हैं ?

'माया' सर्वे के अनुसार ८५६ लोगों में से ५०७ लोगों अर्थात ५९.२२ प्रतिशत ने बताया कि वे बोफोर्स तोपों की खरीदी में हुए दलाली प्रकरण को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इस संबंध में बच्चन बंधुओं पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन अधिकांश अमिताभ-समर्थकों का कहना है कि राजीव गांधी ने अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया।

प्रश्न—१० : कौन अधिक ईमानदार है ?

'माया' सर्वे टीम ने मतदाताओं के सामने सवाल रखा था कि वे राजीव, वी०पी० सिंह और अमिताभ में से किसे अधिक ईमानदार मानते हैं ? इसके जवाब में २०२ अर्थात २३.५६ प्रतिशत मतदाताओं ने राजीव को, ३५४ अर्थात ४१.३५ प्रतिशत ने वी०पी०

मतदाता का रुख

	१९८४ में किसे वोट दिया?				१९८८ के उपचुनाव में किसे वोट देंगे?			
जातीय स्थिति	संख्या	अमिताभ	बहुगुणा	अन्य	अमिताभ	वी०पी० सिंह	बहुगुणा	अन्य
हरिजन	२१२	१५६	५५	१	१२०	५०	४१	१
वैश्य	१४०	८५	५२	३	६३	३६	३८	३
ठाकुर	६६	४३	२०	३	२१	२९	१४	२
ब्राह्मण	२२८	१६४	५४	१०	११३	६३	४५	७
मुस्लिम	११३	७६	३७	-	६४	१२	३७	-
कायस्थ	९७	६८	१७	१२	५०	२३	१९	५
योग	८५६	५२९	२३५	२९	४३१	२१३	१९४	१८
प्रतिशत		६१.१६	२७		५०.३५	२४.८८	२२.६६	

अमिताभ का औचित्य?

जातीय स्थिति	कुल संख्या	क्या अमिताभ का इस्तीफा देना उचित था?		क्या अमिताभ का फिर से चुनाव लड़ना उचित है?	
		हां	नहीं	हां	नहीं
हरिजन	२१२	५७	१५५	१३७	७५
वैश्य	१४०	५४	८६	८१	५९
ठाकुर	६६	३२	३४	२८.	३८
ब्राह्मण	२२८	९८	१३०	१३७	९१
मुस्लिम	११३	४७	६६	५९	५४
कायस्थ एवं अन्य	९७	३८	५९	५२	४५
योग	८५६	३२६	५३०	४९४	३६२
प्रतिशत		३८	६२	५७.७१	४२.२९

सिंह को और २५६ अर्थात ३०.२५ प्रतिशत ने अमिताभ को ईमानदार बताया। ४१ मतदाता तीनों को बेईमान मानते हैं।

प्रश्न—११: बेहतर प्रत्याशी कौन हैं?

इलाहाबाद के आसन्न उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के रूप में मतदाताओं के सामने वी०पी० सिंह, अमिताभ बच्चन, भूरेलाल, एन०डी० तिवारी, बहुगुणा और सोनिया गांधी के नाम रखे गये थे। ८५६ मतदाताओं में से सर्वाधिक अर्थात ३८.६६ प्रतिशत मतदाताओं ने अमिताभ बच्चन को बेहतर प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन वी०पी० सिंह को बेहतर प्रत्याशी माननेवाले २४.०६ प्रतिशत और २२.५४ प्रतिशत बहुगुणा समर्थकों को जोड़ दिया जाये, तो संयुक्त विपक्ष अमिताभ पर भारी पड़ जाते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि एन०डी तिवारी को जहां १५ और भूरेलाल को ३१ मतदाता बेहतर प्रत्याशी मानते हैं, वहीं सोनिया गांधी को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए बेहतर प्रत्याशी माननेवालों की संख्या ८० है।

सर्वे: 'माया' टीम,
विश्लेषण: विनोद मिश्र

त्रिपुरा—मेघालय

वामपंथी किले में कांग्रेस की सेंध

राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद जो सर्वाधिक मनोबल-वर्द्धक बात हुई है, वह है पूर्वोत्तर में वामपंथियों के दुर्भेद्य दुर्ग पर कांग्रेसी झण्डा फहराना। केरल में पुनः सत्ता हथिया लेने के बाद विपक्षी राजनीति में वापपंथी निर्णायक भूमिका अदा करने की स्थिति में आ गये थे। ९ दिसंबर को दिल्ली में विशाल रैली आयोजित करके उन्होंने अपनी धाक और जमा ली थी। इधर वामपंथी दलों के बढ़ते हौसले और उधर एक-के-बाद-एक राज्यों का इंका के हाथ से खिसक जाने और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राजीव गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिह्न लग रहा था। हरियाणा में कांग्रेस के सफाये के बाद यह माना जा रहा था कि अब हिन्दी क्षेत्र में भी इंका की कब्र खुदने लगी है। लेकिन पहले नागालैंड में और अब त्रिपुरा में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेसियों को यह कहने का बल दे दिया है कि राजीव गांधी की लोकप्रियता अक्षुण्ण है।

त्रिपुरा में कुल मतदाताओं की संख्या १३,४०,९०१ है और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या ६०। इस बार ५९ स्थानों के लिए चुनाव हुआ। एक स्थान पर चुनाव रद्द कर दिया गया, क्योंकि सी०पी०एम० के प्रत्याशी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। इस चुनाव में कांग्रेस-टीयूजेएस गठबंधन ने ३१ स्थान जीते हैं।

त्रिपुरा में कांग्रेस की जीत निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। जो पार्टी १९७७ में एक भी स्थान नहीं जीत पायी थी, उसने इस बार २४ स्थानों पर कब्जा कर लिया और अपनी सहयोगी पार्टी त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति के ७ विधायकों को मिलाकर ५ फरवरी को त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर रंजन मजुमदार के नेतृत्व में सरकार बना ली। १९८३ में सी०पी०एम० ने ३७ सीटें जीती थीं और आर०एस०पी० की दो सीटें मिलाकर मोर्चे के ३९ विधायक थे, लेकिन इस बार सी०पी०एम० ने ११ सीटें खो दी हैं।

वाममोर्चे की हार का मुख्य कारण ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स (टी०एन०वी०) की बढ़ती हिंसा पर काबू न कर पाना है। वाममोर्चा लगातार यह कहता रहा है कि इस समस्या का समाधान राजनीतिक है, सैनिक नहीं। लेकिन मोर्चा न कबायली जनता को अपने विश्वास में ले पाया न ही टीएनवी गुरिल्लों को लगाम लगा पाया। परिणाम यह हुआ कि बंगाली जनता में असुरक्षा की भावना प्रबल होती चली गयी। यद्यपि चुनाव के ऐन मौके पर प्रांत को सेना के हवाले सौंपने को राजनीति से प्रेरित कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सेना की तैनाती से गैरकबायली लोगों में यह भावना पैदा हुई कि वाम मोर्चे के पास हिंसा को रोकने की इच्छाशक्ति और प्रशासनिक ताकत नहीं है। यह काम केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। परिणामतः उत्तरी जिलों के बंगलाभाषी मतदाताओं ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया। फौज की तैनाती के बाद ९० प्रतिशत तक मतदान हुआ, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। जो कांग्रेस-समर्थक मतदाता टीएनवी के डर से मतदान में भाग लेने से कतराते थे, वे इस बार बेधड़क मतदान केंद्रों में पहुंचे।

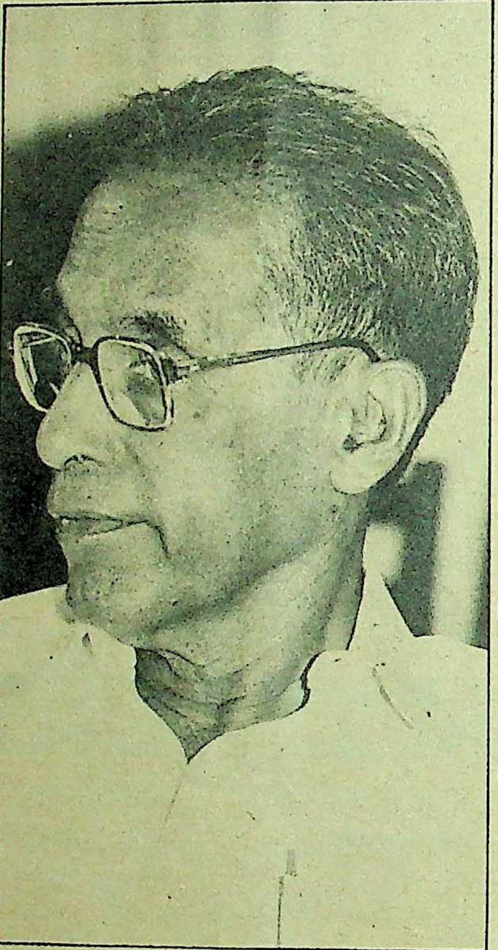

टी०एन०वी० ले डूबा : नृपेन चक्रवर्ती

यद्यपि कांग्रेस त्रिपुरा में सरकार बनाने में सक्षम हो गयी है, लेकिन उसके अति उत्साहित होने का कोई कारण नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसके पास वाममोर्चा से तीन ही विधायक अधिक हैं। उनमें से एक के विधानसभा अध्यक्ष बन जाने पर यह संख्या ३० रह जायेगी। ऐसी नौबत बार-बार आ सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष को मतदान में भाग लेना पड़े। ऐसी स्थिति में त्रिपुरा की स्थिति में स्थायित्व का अभाव रहेगा।

मेघालय : त्रिपुरा में आतंकवाद के हावी होने से यदि नृपेन चक्रवर्ती को सत्ता से वंचित होना पड़ा है, तो मेघालय में कैप्टेन विलयम्सन संगमा को भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ी है। ६० सदस्यों की विधानसभा में पहले कांग्रेस के पास ३६ सदस्य थे, लेकिन अब घट कर २२ रह गये हैं, दूसरी ओर उसकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी हिल पीपुल्स यूनियन ने १५ से बढ़ा कर अपनी संख्या १९ कर ली है।

कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण है क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज करना। खासी विद्यार्थी संघ के लगातार आंदोलन से उसकी स्थिति और कमजोर हुई। खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में कांग्रेस का समर्थन बढा है, जबकि गारो क्षेत्र में उसका समर्थन घटा है। यह ताज्जुब की बात है कि कैप्टेन डब्ल्यू संगमा गारो हैं, लेकिन जहा १९८३ में यहा १८ सीटें मिली थीं, वहां अब ७ रह गयी हैं, जबकि खासी-जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पहले ७ थी, तो अब दुगनी हो गयी है। राज्यसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष जी०सी० स्वेल के विद्रोही रुख के कारण भी कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है।

यो तो मेघालय में सबसे बड़ी अकेली पार्टी कांग्रेस है, लेकिन सरकार बनाने की कुंजी निर्दलियों के पास है जो ९ सीटों पर विजयी हुए हैं। इनमें से ५ विद्रोही कांग्रेसी उम्मीदवार हैं। स्वेल समर्थक भी दो विधायक हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय श्रममंत्री पी० संगमा को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में उतारा था। उन्होंने जीत हासिल की है और अब वह मुख्यमंत्री भी चुन लिये गये हैं। हिल पीपुल्स यूनियन के अध्यक्ष बी०बी० लिंगडोह ने उनसे सहयोग करने के लिए कहा है। जाहिर है जोड़-गांठ से बनी सरकार १९७२ से प्रांत में चली आ रही अस्थिरता को स्थिरता में नही बदल सकती।

लेकिन प्रांतीय स्तर से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर इन चुनावों का असर होगा—खासकर त्रिपुरा में हुए सत्ता परिवर्तन का, क्योंकि वामपंथी तीन राज्यों—केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा—में सत्तारूढ़ होने के कारण अपनी शर्तों पर विपक्ष की एकता चाहते थे। उनकी रणनीति भाजपा को अलग-थलग कर देने की थी। वाममोर्चा के वी०पी० सिंह भी इसी हवा में बह रहे थे। लेकिन अब इस धारणा को बल मिलेगा कि भाजपा और लोकदल-ब को अलग रख कर हिंदी क्षेत्र में विपक्ष कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। वाममोर्चा की मुसीबतें पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और अब वे पश्चिमी बंगाल में भी त्रिपुरा की पुनरावृत्ति के सपने संजोयेंगे।

—विशेष प्रतिनिधि

RADIO
CENTRE

दुबारा राजतिलक : शिवचरण माथुर पद की शपथ लेते हुए

हरिदेव जोशी

हटे या हटाये गये ?

राजस्थान में ऐसा संकट नहीं था जैसा उड़ीसा और बिहार में है, लेकिन इसके बावजूद इंका आलाकमान ने हरिदेव जोशी को हटाकर शिवचरण माथुर को गद्दीनशीं कर दिया है। राजा मानसिंह की हत्या के बाद सत्ताच्युत हुए माथुर को चाहे पुनः गद्दीनशीं अमिताभ बच्चन ने करवाया हो या बूटा सिंह ने, लेकिन राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। माथुर को सभी विधायकों का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। जिस व्यक्ति को मंत्रिमंडल के आधे-अधूरे गठन में पांच दिन लगा हो, क्या वह व्यक्ति पार्टी और सरकार को एकजुट रखते हुए प्रांत के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के साथ ही हरिदेव जोशी ने आलाकमान के सामने भविष्य में 'चुनौती' का खतरा खड़ा कर दिया है। त्यागपत्र देने में आनाकानी करकें उन्होंने यह भी जता दिया कि पुराने कांग्रेसियों को आलाकमान अथवा प्रधानमंत्री का हुक्म बजाने के लिए संगठन के छुटभैय्या राजनेता मजबूर नहीं कर सकते। यही वजह थी कि जब पन्द्रह जनवरी को राजस्थान के मामलों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किये गये केन्द्रीय गृहमंत्री बूटासिंह ने श्री जोशी को प्रधानमंत्री की इच्छा से अवगत कराते हुए त्यागपत्र देने की बात कही, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पहले प्रधानमंत्री से बात करूंगा। जानकार लोगों का कहना है कि श्री बूटासिंह को यह जवाब बड़ा नागवार लगा। पूर्व में भी बूटासिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र जालोर के कई काम श्री जोशी को बता चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कभी भी बड़ा नेता स्वीकार नहीं किया।

बूटा का आदेश टाला : दिल्ली से लौटने पर 'माया' ने जब श्री जोशी से सम्पर्क किया, तो उनका पारंपरिक शैली में बयान था, "इस्तीफा देने की क्या बात, मुझे तो संकेत तक नहीं मिला है।" फिर भी सच हरिदेव जोशी के बयान के विपरीत था। उधर दिल्ली में आलाकमान के नेता अलग-अलग बात कह रहे थे। मसलन, राजस्थान मामलों के प्रभारी नरेश चतुर्वेदी ने १६ जनवरी को कहा कि राजस्थान में नेतृत्व नहीं बदलेगा। महासचिव जी०के० मूपनार का कहना था मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। स्वयं गृहमंत्री बूटासिंह कह रहे थे, "मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता।" वस्तुस्थिति जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अशोक गहलोत से दिल्ली में सम्पर्क साधा, तो उनका कहना था, "स्वयं जोशीजी से पूछ लीजिए।" जब उन्हें जोशी जी का बयान सुनाया गया, तो उनका जवाब था, "जोशी जी दिल्ली आ रहे हैं, जब वापस लौटें तो पूछना।"

१७ जनवरी को जोशी राजकीय विमान से अपने निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा गये हुए थे। शाम को जयपुर लौटने पर उन्हें तुरंत दिल्ली पहुंचने के निर्देश मिले। दिल्ली पहुंचने के बाद श्री जोशी ने कांग्रेस महासचिव मूपनार से मुलाकात की। आधा घंटे की इस मुलाकात में श्री जोशी से त्यागपत्र न देने का कारण पूछा गया। बताया जाता है कि जोशी ने आलाकमान के फैसले को केन्द्रीय गृहमन्त्री द्वारा सूचित करने पर अपनी नाराजगी प्रकट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशीजी ने महासचिव को स्पष्ट कर दिया था कि वह आलाकमान से मिलने के बाद ही इस्तीफा देंगे। श्री जोशी के इस निश्चय को आलाकमान ने सम्मान नहीं दिया। १९ जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात निश्चित थी, पर हर दो घंटे में प्रधानमंत्री सचिवालय ने मिलने का समय बदला। बहरहाल सायंकाल चार बजे श्री मूपनार के साथ दिल्ली के साउथ ब्लाक स्थित प्रधानमंत्री के कार्यालय में श्री जोशी को बुलाया गया। बीस मिनट की इस मुलाकात में क्या बात हुई, यह बताने के लिए

माथुर के पैरवीकार : प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष अशोक गहलोत (काले कोट में)

श्री जोशी तैयार नहीं थे, पर उनका चेहरा बता रहा था कि प्रधानमंत्री ने बूटासिंह का निर्देश न मानने पर अपनी नाराजगी प्रकट की थी। इस मुलाकात के बाद श्री जोशी सायंकाल छह बजे जयपुर लौटे और सीधे राजभवन पहुंच कर अपना त्यागपत्र कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश शरण वर्मा को सौंप दिया।

हरिदेव जोशी के त्यागपत्र के साथ ही राजनीतिक हलकों में यह बहस छिड़ गयी कि अचानक ऐसे कौन से कारण पैदा हो गये जिनकी वजह से श्री जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा? हालांकि माया को उन्होंने बताया, "कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैंने त्यागपत्र दिया है।" व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या थीं, यह बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। यह पूछने पर इन परिस्थितियों के लिए क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गहलोत जिम्मेवार हैं? श्री जोशी का कहना था, "मेरी उनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई है।"

यह तो तय है कि श्री जोशी के त्यागपत्र के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अथवा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की मुहिम जिम्मेवार है। शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया तो श्री जोशी के मनोनयन अथवा तथाकथित निर्वाचन के दिन १० मार्च, १९८५ से ही उनका विरोध करते रहे हैं, पर आलाकमान ने कभी भी इनके आरोपों को गम्भीरता से नहीं लिया। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत को कभी श्री जोशी की शिकायत करने की जरूरत प्रधानमंत्री के सामने नहीं पड़ी। उनका काम असंतुष्ट करते रहे। उन्हें केवल असतुष्टों के ज्ञापनों का विश्लेषण भर प्रधानमंत्री के सामने रखना होता था।

इस्तीफे के कारण: इस बीच दिवराला में नारी दहन की घटना और उससे जुड़ा धर्मरक्षा समिति का आंदोलन हुआ। इस घटना ने दूसरी बार विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री को दकियानूसी साबित किया था। शाहबानो के मामले में प्रधानमंत्री ने मुस्लिम कानून में हस्तक्षेप करने से अपने को रोक लिया था। ठीक इसी तरह नारी दहन के मामले में राजस्थान की जोशी सरकार निष्क्रिय थी, पर विश्वव्यापी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को सती विरोधी कानून बनाना पड़ा। प्रधानमंत्री के इस बदले हुए रुख से जोशी नावाकिफ रहे जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और उनके अनुयायी मुख्यमंत्री के विरुद्ध सक्रिय हो गये। पहली बार नवम्बर '८७ में प्रदेश कांग्रेस संगठन मंत्री एवं युवा विधायक राजेन्द्र चौधरी ने गहलोत समर्थक विधायकों के साथ प्रधानमंत्री को श्री जोशी के खिलाफ ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के बाद आलाकमान ने नरेश चतुर्वेदी को जयपुर यह पता लगाने भेजा था कि श्री जोशी को कांग्रेस विधायक दल में बहुमत प्राप्त है या नहीं? बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि अधिकांश कांग्रेस विधायक श्री जोशी के साथ हैं। श्री चतुर्वेदी नेतृत्व परिवर्तन की बात से १६ जनवरी तक इनकार करते रहे, पर प्रधानमंत्री देर से ही सही, पर श्री जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी तथाकथित छवि सुधारने का निश्चय सरिस्का में ही कर चुके थे। श्री गहलोत समर्थक विधायकों के ज्ञापन देने के बाद ही प्रधानमंत्री ने सरिस्का में श्री जोशी को फिजूलखर्ची पर नाराजगी का नाटक दिखाया था। श्री जोशी इस हादसे के बाद भी अपने पद के संबंध में आश्वस्त थे। उन्हें समर्थन के संख्याबल पर बड़ा भरोसा था। असंतुष्टों को सबक सिखाने के लिए श्री जोशी ने प्रदेश कांग्रेस महासचिवों में से एक विधायक सी०पी०. जोशी को अपने पक्ष में कर लिया। १३ जनवरी को विधायक जोशी ने पन्द्रह विधायकों के साथ मिलकर राजीव गांधी को एक तार भेजकर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें फैलाकर दूषित वातावरण बनाने के कथित कुत्सित प्रयास को रोकने की मांग की थी। इन विधायकों ने अपने तार में दावा किया था कि कांग्रेस-इ विधायक दल की बड़ी तादाद जोशी नेतृत्व में गहरी आस्था रखती है, जबकि चन्द विधायक स्वार्थवश नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें फैला रहे हैं। इसी तरह विधायक मानसिंह देवड़ा ने जोशी नेतृत्व में गहरी

कैसे हैं शिवचरण माथुर?

शिवचरण माथुर को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी १९८५ में डीग के निर्दलीय उम्मीदवार एवं जाट नेता राजा मानसिंह हत्याकाण्ड के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। इस घटना ने विधानसभा चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया तथा राजस्थान में लोप होता विपक्ष २०० सीटों में से ८५ पर काबिज हो गया। राजा मानसिंह आजादी के बाद निरन्तर चुनाव जीतने वालों में से एक थे। जाति के आधार पर चलने वाली राजनीति के रहते हुए शिवचरण माथुर का पुनः मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस-इ के वजूद के लिए एक समस्या होगी। १९९० के आम चुनावों का सामना श्री शिवचरण माथुर के नेतृत्व में कांग्रेस-इ कैसे करेगी, यह तो वक्त ही बतायेगा। बहरहाल, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोशी के विरुद्ध योजना के आंकड़ों और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की स्वीकृत राशि लैप्स हो जाने के आरोप-प्रत्यारोपों से आक्रमण प्रारम्भ किया था। नतीजे में उन्हें २० जनवरी, १९८८ को पुनः मुख्यमंत्री पद हासिल हुआ है।

श्री माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के नाडी कानूनगो गांव में १४ फरवरी, १९२६ को हुआ। उदयपुर से कला स्नातक बनने के साथ-साथ मेवाड़ प्रजामण्डल द्वारा चलाये किसान आन्दोलन में सक्रिय हुए। इसके बाद वह १९५७-५८ में भीलवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष बने और १९६१ से ६४ तक भीलवाड़ा जिला परिषद के प्रमुख रहे। १९६४ में पहली बार भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में इसी जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधानसभा के सदस्य बने।

सन १९६७ से १९७६ की अवधि में श्री माथुर राज्य सरकार में मंत्री रहे। चौदह जुलाई, १९८१ में वह जगन्नाथ पहाड़िया की जगह मुख्यमंत्री बनाये गये।

आस्था प्रकट करने का बयान जारी कर गहलोत पक्ष के असतुष्ट विधायकों को आड़े हाथों लिया।

प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष अशोक गहलोत ने इन घटनाओं को आलाकमान के सामने कैसे पेश किया, यह तो ज्ञात नही हो सका, लेकिन इसके दो दिन बाद ही केन्द्रीय गृहमंत्री श्री बूटा सिंह और महासचिव जी०के० मूपनार ने श्री जोशी को त्यागपत्र देने के लिए कह दिया। पन्द्रह जनवरी को श्री जोशी अलवर के निकट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन के उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने गये थे। उद्घाटन के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें रात दिल्ली में गुजारनी थी, पर बूटासिंह और मूपनार से इस्तीफे की बात सुनकर वह तुरन्त जयपुर लौट आये। श्री जोशी के प्रधानमंत्री से बात करने के हठ को आलाकमान ने सहजता से नहीं लिया। इसका अहसास उद्घाटन की खबर को दूरदर्शन पर देखकर हुआ। दूरदर्शन पर प्रसारित इस खबर में मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन के अंश नहीं दिखाये गये साथ ही यह बात भी उड़ा दी गयी कि कारखाने का उद्घाटन उन्होंने किया था।

श्री जोशी की संख्याबल में आस्था ने कांग्रेस हाईकमान को काफी चौंकाया है। राजस्थान मामलों के प्रभारी महामंत्री श्री नरेश चतुर्वेदी जहां श्री जोशी के विधायक दल में बहुमत से उन्हें बेहतरीन करार दे गये थे, वहीं श्री जोशी का संख्या प्रेम आलाकमान के दूसरे लोगों को भयभीत कर रहा था। इसकी वजह श्री जोशी की अपने सोच की स्वतंत्र शैली रही है। मसलन वह विपक्ष के नेताओं से दूरी की बात को ठीक नहीं मानते हैं। विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में भी वह उसी तरह राहत पहुंचाते रहे हैं जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचाते थे। श्री जोशी के जनप्रिय बनने के इस प्रयास को आलाकमान ने उचित नहीं माना। उन्हें लगा कि इस तरह श्री जोशी बहुमत के समर्थन के नाम पर आलाकमान के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं। दरअसल, श्री जोशी वही गलती कर गये जो जुलाई १९७१ से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत श्री मोहन-लाल सुखाड़िया ने की थी। कांग्रेस विधायकों के बहुमत से निर्वाचित श्री सुखाडिया मानते थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति गिरि के निर्वाचन में आनाकानी करने के बावजूद उनसे त्यागपत्र मांगने जैसा दुस्साहस नहीं करेंगी। श्रीमती गांधी को यह पसन्द नहीं आया था और जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचन समाप्त हुआ, बहुमत का समर्थन होने के बावजूद श्री सुखाड़िया से त्यागपत्र ले लिया गया।

नये मुख्यमंत्री का चुनाव: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में तभी से विधायक दल का नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आलाकमान द्वारा मनोनीत होता है। श्री जोशी इस परम्परा के खिलाफ अपने मामले में आलाकमान से उलझ गये। उन्होंने प्रधानमंत्री की इच्छानुसार त्यागपत्र तो दे दिया, पर विधायक दल का नेता बहुमत के आधार पर चुने जाने के लिए जोर देते रहे। यही कारण था कि १९ एवं २० जनवरी की रात आलाकमान ने श्री जोशी की जगह मुख्यमंत्री निर्वाचित करने के लिए दो महासचिव नरेश चतुर्वेदी, श्री मूपनार और दो पर्यवेक्षकों के रूप में पूर्व महासचिव आर०एल० भाटिया तथा पूर्व मंत्री शंकरानन्द को भेजा।

इस बीच आलाकमान के उम्मीदवार के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर सामने आ गये थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत का

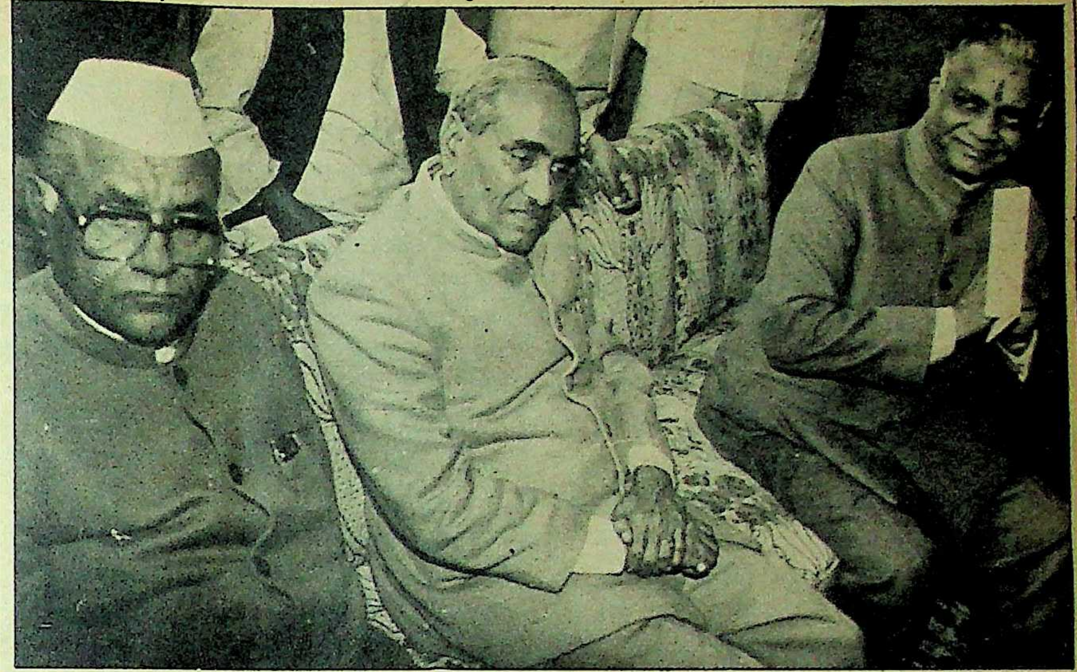

ताजपोशी के तुरंत बाद: मायूस जोशी और देवपुरा के साथ प्रसन्न माथुर

विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता एव भाजपा विधायक भैरोंसिह शेखावत ने श्री जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "जोशीजी को विपक्ष के कारण मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसी के कारण हटाया गया है।" राजस्थान में विपक्ष को धुरी मानकर ही कांग्रेस-इ का संचालन किया जा रहा है। अब उसमें विपक्ष की चुनौती स्वीकार करने की न तो क्षमता है और न ही ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसकी जनता में थोड़ी बहुत साख हो। माया ने जब उनसे कांग्रेस-इ के असंतुष्टों के इस आरोप पर प्रतिक्रिया चाही कि जोशी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया, तो श्री शेखावत का कहना था कि ऐसे लोग भी भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं जो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस शासन के दिन गिनती के हैं। चुनावों में इनको अपनी औकात का पता लग जायेगा।

जनता पार्टी के नेता माणक चन्द सुराणा श्री जोशी को दिल्ली की कृपा से बने मुख्यमंत्री मानते थे। उनका कहना था कि दिल्ली दरबार नाराज हुए तो जोशीजी को विदा होना पड़ा। जोशी शासन के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जोशी राजस्थान में प्रतिक्रियावादी, दकियानूसी व जन विरोधी नीतियों का अम्बार छोड़ गये हैं, जिसे साफ करने में नये मुख्यमंत्री को कठिन प्रयास करने पड़ेंगे।"

कांग्रेस-इ का आंतरिक जनतंत्र

आलाकमान के पर्यवेक्षक बी० शंकरानन्द ने शिवचरण माथुर के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा करते हुए कहा था कि सारा निर्वाचन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, जबकि प्रस्ताव रखते समय श्री जोशी की शब्दावली थी, "आलाकमान के आब्जरवर्स से मुझे पता चला है कि पार्टी विधायकों का बहुमत शिवचरण माथुर के पक्ष में रहा है इसलिए मैं नये नेता के लिए उनके नाम का प्रस्ताव करता हूं।" श्री जोशी की इस शब्दावली से स्पष्ट होता है कि वास्तविकता क्या थी। जोशी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हीरालाल देवपुरा ने भी बुझेमन से प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। इसी तरह समर्थन के नाम पर भी विरोध सामने आया। आलाकमान की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक बी० शंकरानन्द ने पहाडिया का समर्थन करने का इशारा किया, तो उन्होंने खिसियाते हुए समर्थन किया।

समर्थन प्राप्त था। श्री जोशी को आलाकमान के इस सोच की पहले से खबर थी। उन्होंने शिवचरण माथुर के मुकाबले अपने मंत्रिमंडल के सदस्य हीरालाल देवपुरा को अपना उम्मीदवार बना लिया। अनुसूचित जाति के नेता बने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया शक्ति परीक्षण की इस घड़ी में अपने अवसर की बांट जोह रहे थे। १६ जनवरी की रात जब केन्द्र से आये पर्यवेक्षक विधायकों की राय जान रहे थे, तो माथुर और गहलोत समर्थक विधायकों का एक ही बयान था कि उन्हें आलाकमान का तय किया कोई भी नाम मंजूर होगा, जबकि जोशी समर्थक विधायक देवपुरा और पहाड़िया समर्थक विधायक पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाये जाने पर जोर डाल रहे थे। अनुमानतः कांग्रेस विधायक दल के ११५ में से ७० विधायक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ थे। पर्यवेक्षकों को इस गणित का अहसास होने के साथ ही एकमत से नेता चुने जाने की बात होने लगी। अंततः दिल्ली का रुख देखकर पहाड़िया शिवचरण माथुर के पक्ष में आ गये जबकि श्री जोशी को संख्याबल का अभिमान त्यागना पड़ा। बीस जनवरी की सुबह प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में विधायक दल नेता पद के लिए शिवचरण माथुर का नाम निवर्तमान मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और जोशी मंत्रिमंडल के सदस्य हीरालाल देवपुरा ने किया।

शिवचरण माथुर के मुख्यमत्री बनं जाने के बाद 'माया' ने उनसे पूछा, "आप श्री जोशी के कार्यकाल को कैसा मानते हैं?" उन्होंने जवाब दिया, "निरन्तरता मानता हूं।"

राजस्थान में इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ बहुत से सवाल खड़े हो गये हैं। एक सवाल यह है कि क्या शिवचरण माथुर राजस्थान में जाट समुदाय की नाराजगी से अपने को बचा पायेंगे? जाट समुदाय पिछले विधानसभा चुनावों में भरतपुर के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिह की मृत्यु के लिए आज तक उनको दोषी मानता है। कांग्रेस-इ दल के विधायक एवं सांसद आलाकमान के इशारे पर श्री माथुर को भले ही अपना नेता स्वीकार लें, पर जाट एवं किसान जमात पर आधारित लोकदल-अ और ब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान संवेदनाओं को जरूर हवा देंगे। यह तथ्य कांग्रेस-इ के लिए उन स्थितियों में और घातक हो सकता है जब विपक्षी दल मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हों। श्री जोशी के लोकदल-ब के नेता नाथूराम मिर्धा और जनता पार्टी के राजपूत नेता कल्याण सिह कालवी तथा भाजपा के नेता भैरोसिह शेखावत के साथ अंतरंग संबंध रहे हैं। इन संबंधों के परिणामस्वरूप श्री जोशी को विपक्ष का सहयोग प्रान्त की राजनीति और अपने दल के असंतुष्टों से निपटने में मिल जाता था। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को इसके विपरीत विपक्ष से टकराहट का रास्ता अपनाना होगा। विपक्ष से सहयोग की बात सोचना, उनके लिए उसी तरह घातक हो सकता है जिस तरह श्री जोशी के लिए हुआ है।

श्री माथुर इस तथ्य से भी वाकिफ हैं कि कांग्रेस-इ विधायक दल के बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में विधानसभा में उपजने वाला कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उनके नेतृत्व को सार्थक चुनौती देने वाला हो सकता है। इसी तरह अब तक प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष श्री गहलोत को किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का रुतबा हासिल नही था, पर श्री माथुर के संदर्भ में उन्हें यह सफलता भी मिल गयी है। इस रुतबे को प्राप्त करने के बाद सरकार में उनकी दखल स्वाभाविक रूप से बढ़ जायेगी। इस दखल को श्री माथुर का मुख्यमंत्री मन बर्दाश्त कर पायेगा, यह सहज नही लगता। वैसे राजनीतिक हलकों में श्री माथुर को मुख्यमंत्री बनाने में श्री गहलोत के सहयोग को आश्चर्य के साथ लिया जा रहा है। वर्तमान स्थितियों में अगर कांग्रेस-इ के नाराज नेताओं ने बगावत का रुख अपना लिया, तो सत्ताधारी दल के लिए राजस्थान में शासन करना मुश्किल हो जायेगा।

छाया : गोपाल संगर

—ओम सैनी

शिवचरण माथुर

सिर मुड़ाते ही ओले पड़े

शिवचरण माथुर दुबारा से मुख्यमंत्री की कुरसी पर विराजमान तो हो गये, लेकिन लगता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो गये हैं। एक मंत्रिमंडल का गठन करने में ही उनको नानी याद आ रही है। अपने सात सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन के लिए उन्होंने राजीव गांधी के स्टाकहोम से लौटने का इंतजार किया। दूसरी ओर डीग के राजा मानसिंह का भूत भी उनके पीछे लग गया है। स्मरणीय है कि १६८५ में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इसलिए हाथ धोना पड़ा था कि ऐन चुनाव के मौके पर पुलिस के हाथों राजा मानसिह की हत्या हो गयी थी। अब उन्हीं राजा मानसिह के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल, राजीव गांधी के इस बयान ने, कि राजा मानसिह की हत्या में माथुर का कोई दोष नहीं था, मामले को और हवा दे दी है।

राजा मानसिह की विधायक पुत्री सुश्री कृष्णेन्द्र कौर उर्फ दीपा ने माथुर के खिलाफ अभियान छेड़ने की शुरुआत कर दी है। दीपा ने डीग में एक दिवसीय बंद का आयोजन किया। उधर अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भैरो सिह शेखावत के आह्वान पर भाजपा, जनता पार्टी, लोकदल और निर्दलीय विधायकों ने अपना कार्यक्रम तय कर लिया है।

लोकदल-अ विधायक और केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के भतीजे यदुनाथ सिंह भी इस माथुर विरोधी जेहाद में कूद पड़े हैं। श्री सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र में एक रैली आयोजित की जिसमें मुख्यमंत्री माथुर का पुतला भी जलाया गया। नटवर सिंह माथुर विरोधी खेमे के माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि १६८५ में श्री माथुर की मुंख्यमंत्री पद से छुट्टी कराने में उनका हाथ था। उन्होंने माथुर के दोबारा मुख्यमंत्री बनाये जाने का विरोध भी किया था। अतः एक कयास यह भी है कि नटवर सिंह की शह पर ही यदुनाथ इस अभियान को प्रखर बनाने में जुटे हुए हैं।

राजा मानसिह के अलावा एक और ऐसा विवादास्पद मामला है जो श्री माथुर के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में हनुमान प्रसाद प्रभाकर को शामिल किया है। हनुमान प्रसाद को अपनी पुत्री का बाल-विवाह कर देने के खिलाफ उन्हें मंत्रिमंडल मे निकाला जा चुका था।

श्री माथुर ने फरवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात कही है। यह काम भी कोई छोटी समस्या नहीं होगी। इस बात की जानकारी तो सभी को है कि कांग्रेस विधायक दल में उन्हे बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में, सभी को संतुष्ट रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का समर्थन उन्हें जरूर प्राप्त है और वह उनके मंत्रिमंडल में भी हैं, मगर हरिदेव जोशी की तरह संगठन में किसी की पकड़ नहीं है। जोशी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हीरालाल देवपुरा तो उनके खिलाफ हैं ही। ऐसी स्थिति में कब बहुमत विद्रोह पर उतारू हो जाये, कहना मुश्किल है। उनके मौजूदा मंत्रिमंडल में जोशी मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य शामिल नहीं है। इसी से जाहिर हो जाता है कि पुराने और नये मुख्यमंत्री के बीच की टसल जारी रहेगी।

इन सब मुश्किलों से निपटने के बाद सदी का सबसे भीषण सूखा संकट श्री माथुर का इंतजार कर रहा है। सूखा संकट से ठीक ढंग से न निपटना ही श्री जोशी की विदाई का कारण बना था। इस मामले में श्री माथुर की थोड़ी सी कोताही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे पार्टी के अंदर के असंतुष्टों को उंगली उठाने का बहाना तो मिलेगा ही, विपक्ष को भी एक अच्छा खासा मुद्दा हाथ लग जायेगा। ■

दिग्विजय सिंह बनाम राम रतन राम

टकराहट क्यों ?

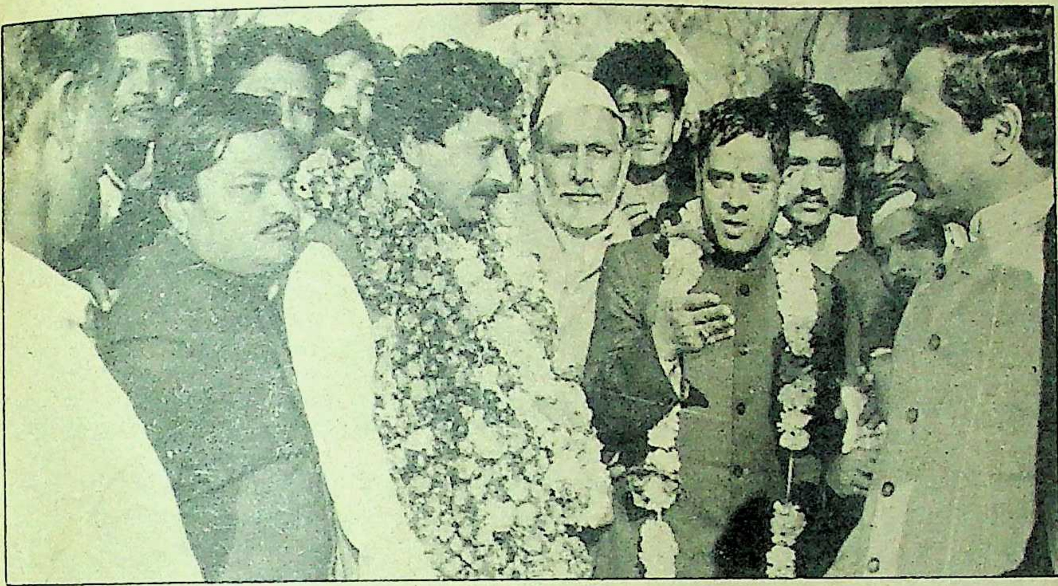

बांयें से, शिखर चंद्र जैन, हैदरयार खां, रसूल अहमद सिद्दीकी एवं माणक अग्रवाल

अखिल भारतीय इंका महासचिव राम रतन राम ने मध्य प्रदेश इंकाध्यक्ष दिग्विजय सिंह से सलाह किये बिना सांसद हैदरयार खां को प्रदेश इंका का संयुक्त सचिव और प्रकाशचंद्र खंडेलवाल को ग्वालियर शहर इंका का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने राज्यमंत्री सिद्दीकी सहित जिन पांच प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ राम रतन राम के साथ भोपाल प्रवास के दौरान कथित दुर्व्यवहार करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की, तो स्वयं राम रतन राम ने उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार के आरोप को असत्य बताते हुए उक्त कार्यवाही रोक देने की अनुशंसा कर दी। दिग्विजय सिंह क्षुब्ध हैं और वह राम रतन राम द्वारा की गयी नियुक्तियों को अवैध मानते हैं। प्रदेश इंकाध्यक्ष और अखिल भारतीय इंका महासचिव आपस में क्यों जूझ रहे हैं? और इसका प्रदेश की इंका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

विवादास्पद दखलंदाजी : राम रतन राम

मध्यप्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों बेतरह खिन्न हैं। कारण यह है कि एक ओर तो संगठन में उनकी राय व उनके महत्व की उपेक्षा की जा रही है, दूसरी ओर सत्ता के हाथों उनकी पूछ-परख कम होती जा रही है। मुख्यमंत्री वोरा समर्थकों की घेराबंदी से वह पहले से ही परेशान थे, ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी के महासचिव और मध्यप्रदेश के प्रभारी राम रतन राम की हरकतों व कतिपय फैसलों ने उन्हें अजीबोगरीब मुश्किल में डाल दिया है। हालत यह हो गयी है कि अगर आलाकमान ने राज्य में संगठन से जुड़े मसलों पर चुप्पी साधे रखी तो कुछ समय बाद प्रदेश इंकाध्यक्ष के तौर पर दिग्विजय सिंह की हैसियत हास्यास्पद हो जायेगी।

टकराव : इंका शासित राज्यों में मध्यप्रदेश संभवतः पहला राज्य है, जहां प्रदेश इंकाध्यक्ष को अखिल भारतीय इंका के प्रभारी महासचिव से टकराना पड़ रहा है। संगठन में अपने वर्चस्व के कारण अभी तक दिग्विजय सिंह को वोरा की राजनीतिक बिरादरी से लोहा लेने में मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, लेकिन प्रदेश में राम रतन राम की निरंतर बढ़ती सक्रियता से स्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन आया और जल्दी ही ऐसी स्थिति आ गयी, जब दिग्विजय सिंह को संगठन को अपने मनमाफिक बनाये रखना और इच्छानुसार चलाना मुश्किल लगने लगा है। ऐसे में उनके समक्ष इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वह अखिल भारतीय इंका के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले को सुलझाने की फरियाद करें।

अध्यक्ष की स्थिति को हास्यास्पद बनाने के सिलसिले की कड़ी के तौर पर पिछले दिनों दो घटनाएं ग्वालियर और भोपाल में घटीं। १४ जनवरी को राजधानी के सभी छोटे-बड़े अखबारों में खबर छपी कि अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी ने भोपाल के हैदरयार खां को मध्यप्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। हैदरयार दो दिनों से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व जेल राज्यमंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी के साथ दिल्ली में डेरा डाले पड़े थे। हैदर की नियुक्ति पर एक तरफ अर्जुन शिविर के लोगों को हैरत हुई, दूसरी ओर दूसरे पक्ष की ओर से बधाइयों का तांता लग गया। बधाई देनेवालों में सांसदों, संगठन-पदाधिकारियों, विधायकों, निगमाध्यक्षों, पूर्व पार्षदों व आम इंकाजनों सभी का समावेश था। १५ जनवरी को हैदरयार रेलगाड़ी से भोपाल आये, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसी शाम मोतीलाल वोरा गुजरात की यात्रा से लौटे, तो रसूल अहमद सिद्दीकी, माणक अग्रवाल, शिखरचंद जैन आदि नेताओं व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पहुंचकर संयुक्त सचिव पद पर हैदरयार की नियुक्ति के लिए वोरा के प्रति आभार व्यक्त किया। समाचारपत्रों में वोरा के साथ प्रफुल्ल मुद्राओं में इन लोगों के बहु-कालमी चित्र भी छपे। इसी दिन हैदरयार खां सौजन्यतावश दिग्विजय सिंह से मिलने गये और उनसे आशीर्वाद मांगा। नेपथ्य के घटनाक्रम से अपरिचित और संयुक्त सचिव पद पर हैदर की सहसा नियुक्ति से हतप्रभ दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें तो इस नियुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है। इस पर हैदरयार ने उन्हें मिला आदेश दिखाया तो इंकाध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, आप काम कीजिये। हैदरयार के मुताबिक राजा साहब ने उन्हें १८ जनवरी को निश्चित दायित्व सौंपने की बात कही थी। लेकिन जब १८ जनवरी को वह दफ्तर नहीं आये, तो फोन करने के बाद वह उनसे मिलने बंगले गये। वहां उन्हें एक ओर ले जाकर प्रदेश इंकाध्यक्ष ने कहा कि राम रतन राम को इस तरह नियुक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। इस तरह से नियुक्ति केवल राजीवजी ही कर सकते हैं।

हैदरयार खां प्रदेश इंकाध्यक्ष के बंगले से बैरंग लौटे, तो उनके राजनीतिक आकाओं और शुभचिंतकों की बिरादरी सलाह-मशविरे के लिए जुटी। अगले दिन हैदर ने दिल्ली फोन लगाकर राम रतन राम को घटनाक्रम का ब्योरा दिया। हैदरयार से 'माया' को मिली जानकारी के अनुसार राम रतन राम ने फोन पर कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी की नियुक्ति वैधानिक होती है और इस बाबत उनसे पूछताछ का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

दूसरा प्रसंग : भोपाल की भांति प्रदेश इंकाध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचाने की एक और

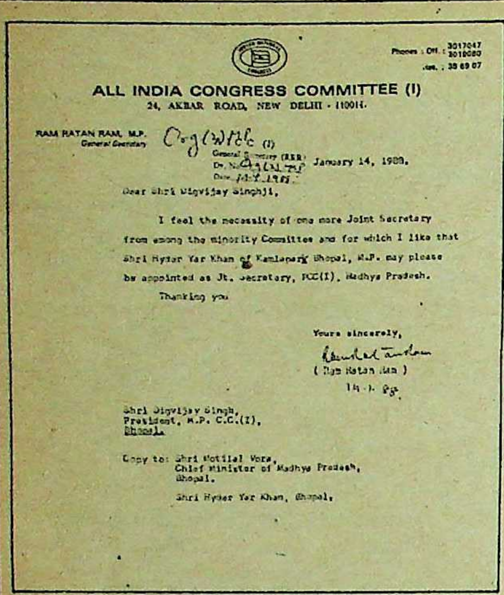

Phones : Off. : 3017047
3019080
Res. : 38 69 07

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE (I)
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI - 110011.

RAM RATAN RAM, M.P.
General Secretary

Org(3)MP (I)

General Secretary (RRR)
Dr. No. Org(3) MP
Date 14.1.1988

January 14, 1988.

Dear Shri Digvijay Singhji,

I feel the necessity of one more Joint Secretary from among the minority Committee and for which I like that Shri Hyder Yar Khan of Kamlapark Bhopal, M.P. may please be appointed as Jt. Secretary, PCC(I), Madhya Pradesh.

Thanking you

Yours sincerely,

(Ram Ratan Ram)
14.1.88.

Shri Digvijay Singh,
President, M.P. C.C.(I),
Bhopal.

Copy to: Shri Motilal Vora,
Chief Minister of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Shri Hyder Yar Khan, Bhopal.

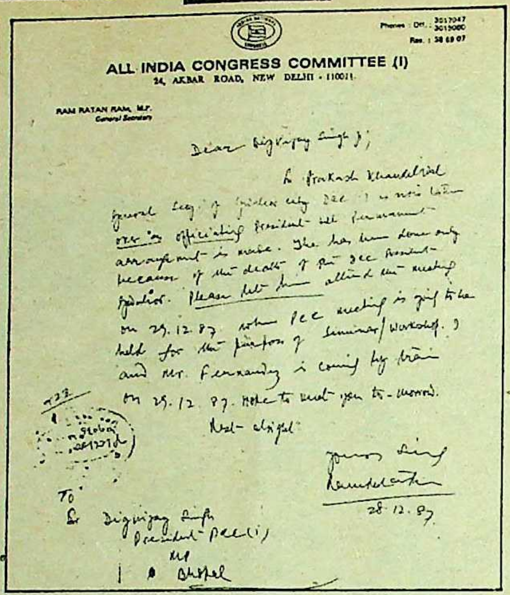

Phones : Off. : 3017047
3019080
Res. : 38 69 07

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE (I)
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI - 110011.

RAM RATAN RAM, M.P.
General Secretary

Dear Digvijay Singh ji,

Sri Prakash Khandelwal General Secy of Gwalior city DCC (I) is now taking over as officiating President till permanent arrangement is made. This has been done only because of the death of the DCC President. Please let him attend the meeting on 29.12.87 when PCC meeting is going to be held for the purpose of Seminar/Workshop. I and Mr. Fernandez is coming by train on 29.12.87. Hope to meet you to-morrow.

Best wishes

Yours sincerely

28.12.87.

To
Sri Digvijay Singh
President PCC(I)
MP
Bhopal

नियुक्ति पत्र : राम रतन राम द्वारा लिखे पत्र

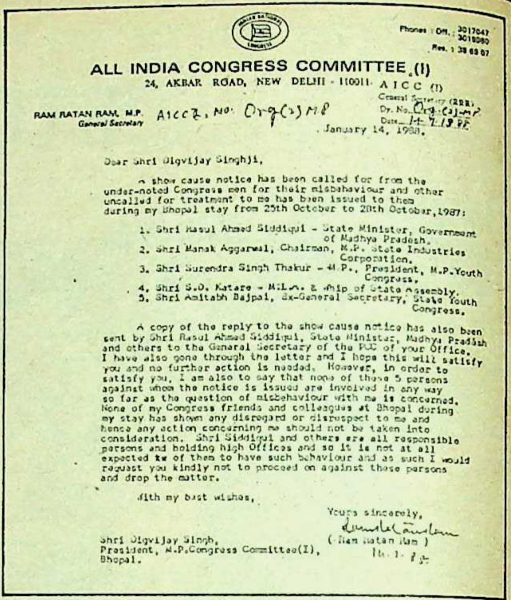

Phones : Off. : 3017047
3019080
Res. : 38 69 07

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE (I)
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI - 110011.

AICC (I)
General Secretary (RRR)
Dr. No. Org(3)MP
Date 14.1.1988

RAM RATAN RAM, M.P.
General Secretary

AICC I. No. Org(3)MP

January 14, 1988.

Dear Shri Digvijay Singhji,

A show cause notice has been called for from the under-noted Congress men for their misbehaviour and other uncalled for treatment to me has been issued to them during my Bhopal stay from 25th October to 28th October, 1987:

1. Shri Rasul Ahmed Siddiqui - State Minister, Government of Madhya Pradesh.
2. Shri Manak Aggarwal, Chairman, M.P. State Industries Corporation.
3. Shri Surendra Singh Thakur - M.P., President, M.P. Youth Congress.
4. Shri S.D. Katare - M.L.A. & Whip of State Assembly.
5. Shri Amitabh Bajpai, Ex-General Secretary, State Youth Congress.

A copy of the reply to the show cause notice has also been sent by Shri Rasul Ahmed Siddiqui, State Minister, Madhya Pradesh and others to the General Secretary of the PCC of your Office. I have also gone through the letter and I hope this will satisfy you and no further action is needed. However, in order to satisfy you, I am also to say that none of these 5 persons against whom the notice is issued are involved in any way so far as the question of misbehaviour with me is concerned. None of my Congress friends and colleagues at Bhopal during my stay has shown any disregard or disrespect to me and hence any action concerning me should not be taken into consideration. Shri Siddiqui and others are all responsible persons and holding high Offices and so it is not at all expected ~~tw~~ of them to have such behaviour and as such I would request you kindly not to proceed on against these persons and drop the matter.

With my best wishes,

Yours sincerely,

(Ram Ratan Ram)
14.1.88

Shri Digvijay Singh,
President, M.P. Congress Committee(I),
Bhopal.

मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ : राम रतन राम का पत्र

घटना शाही नगरी ग्वालियर में घटित हुई। ग्वालियर में शहर इंका के कार्यवाहक अध्यक्ष सुमेर सिह की दिसंबर के अंतिम हफ्ते में मृत्यु हो गयी। सुमेर सिंह के देहांत के बाद भगवान सिह यादव, महाराज सिंह और राजेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पद के दावेदार थे, लेकिन इन सब धुरंधरों को धता बताते हुए महामंत्री प्रकाशचंद्र खंडेलवाल ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया और ३१ दिसंबर को एक अन्य महामंत्री नरेंद्र सिंह ने अपने हस्ताक्षर से प्रेस के लिए वक्तव्य जारी कर खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने की पुष्टि कर दी। बयान के साथ उस पत्र की फोटोप्रति भी अखबारों के दफ्तरों में पहुंची जो राम रतन राम ने दिग्विजय सिंह को लिखा था।

२८ दिसंबर, १९८७ को 'डियर दिग्विजय सिंहजी' के संबोधन से अंग्रेजी में लिखे पत्र में राम रतन राम ने इंकाध्यक्ष को सूचना दी कि स्थायी इंतजाम होने तक प्रकाश खंडेलवाल ने कार्यवाहक अध्यक्ष का कामकाज संभाल लिया है, अतः उन्हें २९ दिसंबर को भोपाल में प्रदेश इंका की बैठक में सम्मिलित होने दें।

कोई ताज्जुब नहीं, अगर संपूर्ण घटनाक्रम की खबर और राम रतन राम की चिट्ठी मिलने पर राजा साहब ने अपना सिर पीट लिया हो। एक तरह से यह उनकी सरासर तौहीन थी। उनके आदेश से स्थायी मंत्री राम नारायण पुरोहित ने दो जनवरी को प्रकाश खंडेलवाल को पत्र लिखकर पूछा कि कार्यवाहक अध्यक्ष का चार्ज आपने किसकी अनुमति से लिया है? सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र में यह लिखा है कि बगैर अनुमति राम रतन राम के प्रदेश इंकाध्यक्ष को संबोधित पत्र को समाचार पत्रों में छपाने की आपकी कार्रवाई को क्यों न गैरजिम्मेदाराना, आपराधिक और अवांछनीय कार्रवाई माना जाये?

राजा साहब के आदेश से लिखे इस खत में दी गयी सात दिनों की मोहलत को गुजरे कई दिन बीत गये हैं, परंतु प्रकाश खंडेलवाल अभी भी पूर्ववत कार्यवाहक अध्यक्ष बने बैठे हैं। राम की भूमिका को छोड़ भी दें, तो पूरे प्रदेश के संगठन के मुखिया यहां इस कारण भी लाचार और असहाय हैं, क्योंकि खंडेलवाल पर केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया का वरद हस्त है। राजा साहब के अंतरंग सूत्रों के अनुसार राजा साहब ने इस प्रसंग में नरमी बरतते हुए राम रतन तक अपना यह मंतव्य पहुंचा दिया है कि प्रकाश खंडेलवाल के बजाय किसी भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिसे महाराज सिंधिया चाहें, को अध्यक्ष बना दिया जाये। स्पष्ट है कि ऐसा होने पर महाराज की शान बनी रहेगी और खंडेलवाल के हटने से दिग्गी राजा की फजीहत भी नहीं होगी।

दोनों प्रकरणों से स्पष्ट है कि एक जमाने के तेजतर्रार, व्यवहारकुशल और खुशमिजाज राजनीतिज्ञ दिग्विजय सिंह संगठन में दिनोदिन शोभा की वस्तु होते जा रहे हैं। आभास तो यही होता है कि वह तेजी से वोरा-रसूल-माणक के बनाये जाल में उलझते जा रहे हैं। हैदरयार को नियुक्ति न देने से दिग्विजय के खिलाफ अल्पसंख्यक नेताओं के बयानों की झड़ी लग गयी है। दूसरी ओर वोरा-रसूल-माणक की तिकड़ी राम रतन राम को पूरी तौर पर साध चुकी है। राम आये दिन भोपाल आते रहते हैं और मध्य प्रदेश आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्हें मुक्तहस्त पत्र लिखने का भी शगल है। हाल में उन्होंने दिग्विजय सिंह को एक खत लिखा है कि रसूल अहमद सिद्दकी, माणक अग्रवाल, सत्यदेव कटारे, सुरेंद्र सिंह ठाकुर और अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ अनुशासन की कोई कार्रवाई न की जाये, क्योंकि ये लोग सम्मानित पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं और इन लोगों ने भोपाल प्रवास के दौरान उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नही किया। उल्लेखनीय है कि आठ महिला विधायकों व ५३ विधायकों की शिकायत के बाद दिग्विजय सिंह के निर्देश पर उनके प्रिय महासचिव ललित श्रीवास्तव ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच की थी। सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार पांचों नेता ललित श्रीवास्तव के आरोप पत्र का उत्तर दे चुके हैं और अब मामले की जांच सांसद असलम शेर खां के हाथों में है और उन्हें २८ फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देनी है।

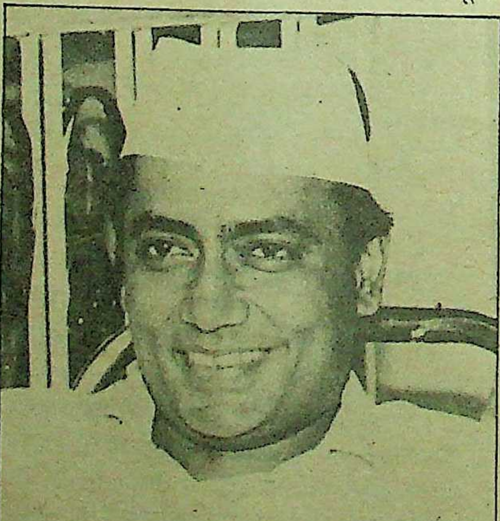

हालत हास्यास्पद : दिग्विजय सिंह

जहां तक हैदरयार की नियुक्ति का प्रश्न है, राम रतन राम ने पत्र में 'मे प्लीज बी अपांइटेड' का इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष के खेमे का कहना है कि यह नियुक्ति नहीं अनुशंसा है और इस प्रकार की कांग्रेस में परिपाटी नहीं है। इसके विपरीत हैदरयार के शुभचिंतकों व आकाओं का कहना है कि मंतव्य बिलकुल स्पष्ट है। पूर्व में दिल्ली से मौखिक आदेश तक पर नियुक्तियां हुई हैं और-तो-और रघुनंदन लाल भाटिया की सामान्य-सी चिट्ठी भी संगठन में नियुक्ति का बायस बन चुकी है। दिग्विजय सिंह राजनीतिक कारणों से इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और ऐसा करके वह सीधे-सीधे अखिल भारतीय कमेटी के महासचिव की अवमानना कर रहे हैं। अध्यक्ष ने हैदरयार को काम भले न सौंपा हो और उनकी नजरों में नियुक्ति भले ही अवैधानिक हो, मगर हैदरयार खां, जो बरसों से जिला इंका के महामंत्री व २० सूत्री समिति के सदस्य हैं, स्वयं को संयुक्त सचिव मानते हैं और उनका कहना है कि वह बहैसियत पदाधिकारी प्रदेश इंका के दफ्तर में बदस्तूर जाते रहेंगे।

—सुधीर सक्सेना

कौन है सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी ?

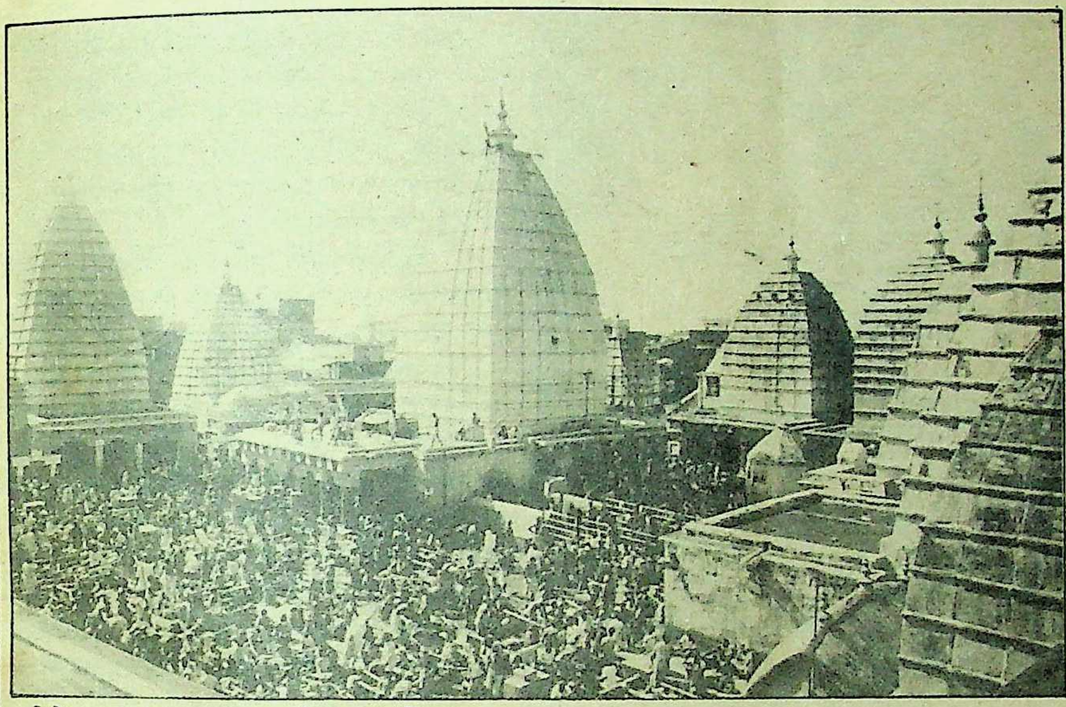

धर्म के बजाय पद पर नजर : बैद्यनाथ मंदिर

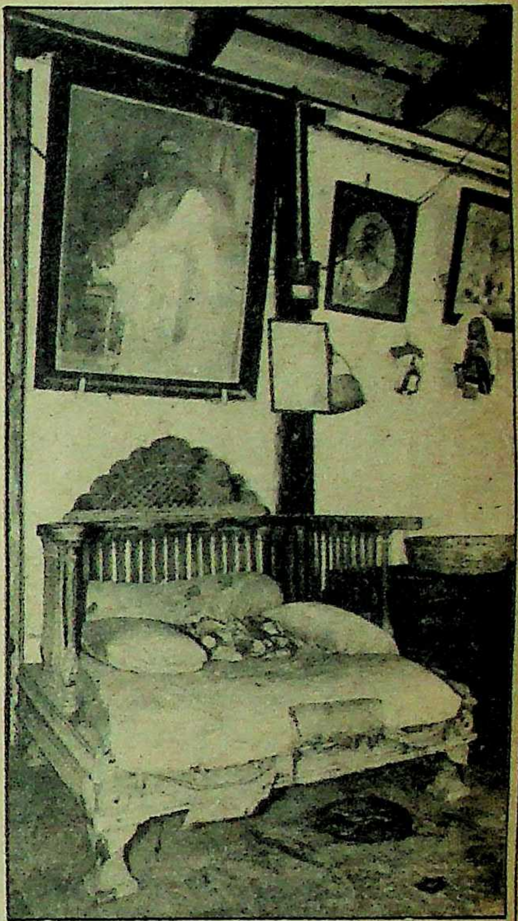

सिंहासन खाली : सरदार पंडा यहां बैठते हैं

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 'सरदार पंडा' पद को लेकर विवाद क्यों छिड़ा है? यहां का बीस हजार पंडा-परिवार कैसा संक्रमण झेल रहा है। देवघर का दुख कौन हरेगा?

पूरे जगत के संकटमोचक बाबा बैद्यनाथ क्या देवघर के पंडा समुदाय पर अप्रसन्न हैं? यह चिंता पूरे पंडा समुदाय को बुरी तरह खाये जा रही है। इस दुश्चिंता के कई ठोस कारण भी हैं। देवघर स्थित पंडों के एकमात्र संगठन 'पंडाधर्मरक्षिणी सभा' के वयोवृद्ध सचिव रतनलाल गैवाल आशंकित होकर कहते भी हैं, "कभी भी कुछ अनिष्ट और अमंगल हो सकता है। पिछले चौदह वर्षों से बाबा भोलेनाथ की 'बड़ी श्रृंगार पूजा' नहीं हो रही है। इस बात से तमाम पंडे बेचैन हैं। बड़ी श्रृंगार पूजा की सभी सामग्री सरकारी ट्रेजरी में बंद पड़ी है।" दरअसल, 'बड़ी श्रृंगार पूजा करने का अधिकार बैद्यनाथ धाम मंदिर के 'सरदार पंडा' का ही है और विगत चौदह वर्षों से 'सरदार पंडा' का पद यहां रिक्त पड़ा है। इस पद पर काबिज होने के लिए कई दावेदार एक दशक से भी अधिक समय से मुकदमेबाजी में मसरूफ हैं। लिहाजा, चिरलंबित फैसले के कारण तमाम पंडे परेशान हैं। पंडों का कहना है कि बिना मुखिया के किसी घर की जैसी दुर्गति होती है, वैसी ही बैद्यनाथ धाम मंदिर की हो रही है।

पंडों की परंपरा : बैद्यनाथ मंदिर के आखिरी सरदार पंडा थे स्व० भवप्रीतानंद ओझा। भवप्रीतानंद बिहार के मुख्यमंत्री स्व० पंडित विनोदानंद झा के भतीजे थे। सरदार पंडा 'शिवस्वरूप' माने जाते हैं। भवप्रीतानंदजी के पूर्व सरदार पंडा थे उमेशानंद झा। वह बड़े नामी पहलवान भी थे। उनके पूर्वज भवप्रीतानंदजी के दादा शैलजानंद ओझा 'सरदार पंडा' थे। 'सरदार पंडा' का पद वंशानुगत होता है। पर भवप्रीतानंदजी के नि:संतान रह जाने के कारण १९७४ में उनके निधन के पश्चात इस पद की दावेदारी का विवाद छिड़ना लगभग तय ही था। भवप्रीतानंदजी के दो सगे भाई थे—स्व० इंद्रानंद झा और स्व० मंगलानंद झा। सरदार पंडा के पद को लेकर इन्हीं दो भाइयों की संतानें अदालत में भिड़ी हुई हैं। स्व० इंद्रानंद के सबसे बडे पोते अजितानंद ने जहां इस पद के लिए दावा ठोंक रखा है, वहीं स्व० मंगलानंद के पुत्र ललितानंद भी इस पद के दावेदार हैं। साथ ही स्व० इंद्रानंद के मंझले पुत्र ज्ञानानंद भी इस दौर में हैं। देवघर के सबडिवीजनल जज की अदालत में चल रहा यह मामला कई बार पटना उच्च न्यायालय में 'रीविजन' के लिए भी गया, पर अभी तक फलाफल नहीं निकल सका है। पंडों का कहना है कि कई बार हमसबों ने मिल-जुल कर फैसला करवाने की कोशिश भी की, पर दोनों गुटों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 'सरदार पंडा' न होने के कारण मंदिर की व्यवस्था के लिए सरकारी स्तर पर एक ट्रस्ट बना है जिसके अध्यक्ष गिद्धौर राजपरिवार के वर्तमान वंशज प्रताप सिंह हैं तथा सदस्यों में मधुपुर से इंका विधायक और स्व० विनोदानंद झा के पुत्र कृष्णानंद झा और पंडासमुदाय के प्रतिनिधि के रूप में हरण मिश्र हैं। मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण डिप्टी कमिश्नर का है। टेंपुल-मजिस्ट्रेट भी नियुक्त है। अधिकांश पंडों की शिकायत है कि ट्रस्ट मंदिर के रख-रखाव के मामले में अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जबकि ट्रस्ट के सदस्य कृष्णानंद झा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। उनका कहना है कि देवघर जब बंगाल का हिस्सा था, तो १९०१ में यह इलाका बर्दवान उच्च-न्यायालय के कानूनी क्षेत्र में था। १९०१ में ही उस न्यायालय ने मंदिर संचालन के सिलसिले में एक व्यवस्था दी जिसमें दो स्थितियों की प्रमुखता से चर्चा की गयी। पहला तो यह कि सरदार पंडा का बड़ा पुत्र जिसकी आयु ४२ वर्ष से कम न हो और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वही 'सरदार पंडा' पद का उत्तराधिकारी हो सकता है। दूसरी परिस्थिति में अगर सरदार पंडा नि:संतान हो, तो सरदार पंडा के वंश का अन्य कोई भी सदस्य सरदार पंडा हो सकता है जिसका चुनाव प्रजातांत्रिक पद्धति

से मतदान् द्वारा पंडे ही करेंगे। कृष्णानंद कहते हैं कि 'सरदार पंडा' न होने के कारण ही ट्रस्ट की व्यवस्था है। समस्याओं के प्रसंग में वह कहते हैं, "मंदिर परिसर में स्थानाभाव है। पंडित विनोदानंद झा जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस सिलसिले में पहल भी की थी कि मंदिर के आसपास के मार्गों की संकीर्णता खतम हो सके। यही नहीं, 'त्रिकुटी हिल' और 'तपोवन' आदि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने की सख्त जरूरत है। पर इसमें अकेले ट्रस्ट क्या कर सकता है?" स्व० चंद्रशेखर सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो तत्कालीन डिप्टी क़मिश्नर अजय ठाकुर ने मंदिर के ठीक सामने स्थित शिवगंगा सरोवर की सफाई का अभियान शुरू किया था जिसको लेकर उनदिनों राजनीतिक हलकों में काफी बावेला भी मचा था। पर शिवगंगा फिर उसी दुर्गति और गंदगी में है। कृष्णानंद कहते हैं, "शिवगंगा के जीर्णोद्धार के लिए पी०एच०इ०डी० विभाग को सरकार से तकरीबन ४८ लाख रुपए भी दिये गये थे, पर एक पाई खर्च नहीं हुआ। शिवगंगा आज भी मैला है।"

"समस्याएं अनंत हैं, पर निराकरण कुछ भी नहीं," कहते हैं युवा पंडा दुर्लभ मिश्र। मंदिर परिसर की कई दीवारें जर्जर और टूटी हुई हैं। सरदार पंडे का जो पारंपरिक—पुश्तैनी निवास था उसे स्थानीय प्रशासन ने बाजार कायम करने के उद्देश्य से तोड़ दिया। पर सरदार पंडा के वंशज अजितानंद ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया तब जाकर बाजार निर्माण का कार्य वहां रुका। पंडों का कहना है कि पौराणिक महत्व के सरदार पंडा निवास को तोड़ दिये जाने से हम सबों को बेहद ठेस पहुंची।

आचार संहिता का उल्लंघन : मंदिर परिसर में ही स्थित है 'भीतर खंड कार्यालय', जहां से मंदिर का प्रबंध होता है। पंडों का कहना है कि सरदार पंडा की जीवितावस्था में इस कार्यालय की पवित्रता बरकरार थी। पर अब उच्च अधिकारियों के लिए कोई आचार संहिता नहीं। सरदार पंडे का सिंहासन वहीं बरामदे में खस्ताहाल पड़ा है। 'भीतर खंड कार्यालय' में ही दुर्लभ श्रीयंत्र और नाथ संप्रदाय का हवनकुंड है जो निहायत बदहाली में है। मंदिर प्रांगण के भीतर के दक्षिणी छोर पर जल निकास का मार्ग था, पर एक स्थानीय व्यवसायी ने मंदिर के बाहर का वह भूखंड जहां जल-निकास था, उसे खरीद लिया और जल-निकास को बंद कर दिया। नतीजतन, मंदिर के दक्षिणी छोर का पानी जमा होकर सड़ता रहता है। मंदिर में पानी का भी गहरा संकट है जिससे रोज हजारों की संख्या में आनेवाले कांवरियों को परेशानी उठानी पड़ती है। मंदिर परिसर या उसके आसपास कहीं एक नल तक की व्यवस्था नहीं है। पंडों का कहना है कि बैद्यनाथ मंदिर के भीतरी द्वार पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए ट्रस्ट से कई बार विनती की गयी, पर आज तक कुछ हुआ नड़ीं।

अनिष्ट की आशंका : रतन लाल गैवाल

पद के प्रमुख दावेदार : अजितानंद

"ट्रस्ट पंडों के हक का अतिक्रमण कर रहा है," कहते हैं—रतन लाल गैवाल। उनके अनुसार, "बैद्यनाथ मंदिर के अंदर पूजन पर बैठे पंडे का अधिकार सदैव से पूजा के दौरान चढ़ावे और दक्षिणा पाने का रहा है। पर मंदिर में तैनात सरकारी प्रशासन अकसर इस पर आपत्ति करता है। आज से लगभग साठ-सत्तर वर्ष पूर्व एक बार 'सरदार पंडा' और आम पंडा समाज के बीच दान-दक्षिणे के सवाल पर बात अदालत तक जा पहुंची थी। अदालत ने उस समय यह फैसला दिया था कि जजमान जो भी चढ़ावा बाबा बैद्यनाथ के माथे पर चढाकर पंडे को दे देगा, वह पंडे का होगा। जो दान माथे पर चढ़ाकर वहीं छोड़ देगा, वह 'सरदार पंडा' यानी मंदिर-व्यवस्था का होगा। रतनलाल कहते हैं कि सावन आदि के समय में जब कांवरियों की भीड़ जमती है, तो मंदिर-प्रशासन मंदिर में पंडों के प्रवेश पर रोक लगा देता है। इस रवैये से सभी क्षुब्ध हैं।"

सुबह चार बजे जब मंदिर का द्वार खुलता है, तब से लेकर दिन के बारह बजे तक जो पंडे पूजन पर होते हैं, वे 'मुसरिफ' कहलाते हैं। शृंगार पूजा करानेवाले शृंगारी कहलाते हैं। देवघर में तकरीबन पचास शृंगारी परिवार हैं। इनके अतिरिक्त 'दुओरी' खानदान भी हैं। श्यामनारायण शृंगारी युवा पंडा हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के अपमानजनक व्यवहार के कारण युवापीढ़ी पंडा-पेशे से विमुख हो रही है। पंडा चंद्रकांत आजाद कहते हैं कि हमारे बच्चे अब विद्रोह करने लगे हैं कि भीख की कमाई हम नहीं खायेंगे।

संक्रमण-काल : महाराजा गिद्धौर के पुश्तैनी पडा सूर्यकांत परिहस्त कहते हैं कि देवघर का तकरीबन बीस हजार पंडा-परिवार अचानक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। सचमुच यह नयी पीढी का संक्रमण काल है। पंडों के नौजवान बेटे अब इस पेशे में हाथ बंटाना सम्मान की बात नहीं समझते, पर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं। पंडा सोनालाल कहते हैं कि पंडों के बेटों को पिता से बस एक ही पूंजी मिलती है—जजमानों की सूची। अगर पिता के पांच बेटे और सौ जजमान हैं, तो बीस-बीस जजमान के हिसाब से बेटे बंटवारा करते रहे हैं, पर नयी पीढ़ी अब इस पेशे को नकार रही है।

मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठानों पर टैक्स भी है। मसलन, मंदिर में मुंडन कराने का टैक्स दो रुपए, बाबा बैद्यनाथ को पगड़ी चढ़ाने का टैक्स दो रुपए, ध्वजा और पाग चढ़ाने का टैक्स एक-एक रुपए लिया जाता है। टैक्स के ये पैसे 'सरदार पंडा' के वंश से संबंधित पंडों में बंटने की परंपरा शुरू से चली आयी है जिसे 'पौना' कहते हैं। यह 'पौना' एक आने से लेकर दस-बारह रुपए तक है। पंडे पूछते हैं, इस 'पौने' से क्या जीवन चलेगा हमारा ? धर्मार्थियों को भी कभी-कभी लगता है कि पंडे उनसे ज्यादा ही वसूली कर लेते हैं, पर पंडे कहते हैं कि हम सब बाबा भोलेनाथ के अनुचर हैं। हमारे खेत-खलिहान नहीं, आजीविका के साधन सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही तो हैं। आखिर पेट को बांध कर तो हम जी नहीं सकते। पंडों का यह भी आक्रोश है कि सरकार उन्हें बसने के लिए जमीन देने के नाम पर भेदभाव कर रही है, जबकि हजारों की तादाद में अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी और धन्ना सेठ देवघर में अवैध ढंग से बस रहे हैं। संथाल परगना टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति यहां जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकता, पर यह काम देवघर में धड़ल्ले से हो रहा है। देवघर के सालौना, बरमसिया, नवाडी, भुरभुरा, पुनसिया और बैद्यनाथपुर आदि हरिजन-बहुल इलाके में गैरकानूनी ढंग से बेहिसाब निर्माण हुए हैं। अभी भी अधिकांश जमीनों का पट्टा हरिजनों के नाम है। देवघर में मंदिर के उत्तरी छोर में पंडों की प्रमुख आबादी है जो लाखराज मौजे के तहत है।

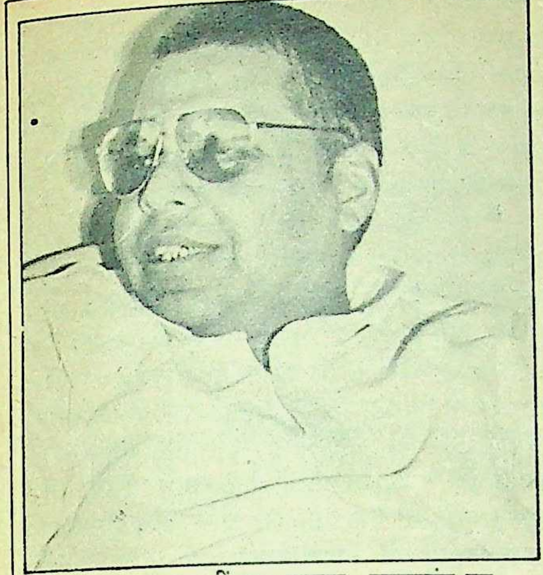

अकेला ट्रस्ट कुछ नहीं कर सकता : कृष्णानंद झा

पंडा सभा अरसे से मांग कर रही है कि नवाडी, बलसरा, सलौना आदि में बहुत सी सरकारी जमीन गैरमजरूआ पड़ी है। पंडे यहां बसने देने की मांग करते रहे हैं। पर सरकार बंदोबस्त नहीं कर रही और सरकारी अधिकारी धड़ल्ले से उन जमीनों पर चढ़े जा रहे हैं।

पंडों को यह बात साल रही है कि उनके बीच पंडित विनोदानंद झा जैसी राजनीतिक शख्सीयत की कमी है। इसलिए न तो मंदिर की समस्याएं हल हो रही हैं, न पंडों की और न देवघर जिले की ही। बिहार राजनीति में गुजरे वक्त में पंडों की महत्वपूर्ण दखल रही। पंडित विनोदानंद झा तो मुख्यमंत्री हुए ही, उनके अलावे रामराज जजवाड़े उन्हीं दिनों में राजमहल से कांग्रेस के सांसद भी चुने गये थे। उसी काल में शिवराम झा भी सामाजिक जीवन में सक्रिय हुए थे। वह 'पंडा धर्म रक्षिणी सभा' के अरसे तक अध्यक्ष भी रहे। वह संथाल परगना के मदनमोहन मालवीय कहे जाते थे। देवघर में हिंदी विद्यापीठ, मातृमंदिर, वेद विद्यापीठ जैसी अनेकों संस्थाओं की यहां उन्होंने स्थापना की। संप्रति विनोदा बाबू के छोटे पुत्र कृष्णानंद झा कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में हैं। स्व० चंद्रशेखर सिंह मंत्रिमंडल में वह राज्यमंत्री भी थे, पर शालीन कृष्णानंद अभी कांग्रेस में अपेक्षित महत्व से दूर कर दिये गये हैं। देवघर सुरक्षित क्षेत्र है जिससे भी उसे घाटा होता है, पर कुछ तटस्थ लोग कहते हैं ऐसा अच्छा ही है। वरना राजनीतिक वर्चस्व के चक्कर में यहां पता नहीं कितना खून खराबा होता ? पर इतना तो जरूर है कि राजनीतिक हैसियत में ह्रास का एहसास तो यहां के लोगों को सालता ही है।

क्या होगा बाबा बैद्यनाथ मंदिर की समस्याओं का, धार्मिक संक्रमण से टूटते-जूझते पंडों के जीवन का ? क्या होगा देवघर का ? धर्मपरायण देवघरवासियों की बस एक ही रट है कि देवघर का दुख सरकार नहीं सिर्फ एक बाबा बैद्यनाथ ही दूर कर सकते हैं।

—विकास कुमार झा

छाया : प्रभाकर

सोने की खोज

बिहार सरकार का खनन एवं भूतत्व विभाग पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई हिस्सों में सोना ढूंढ़ने में जुटा है। पर्याप्त साधनों के अभाव में उसे कितनी सफलता मिलेगी और क्या वहां सोना है भी ?

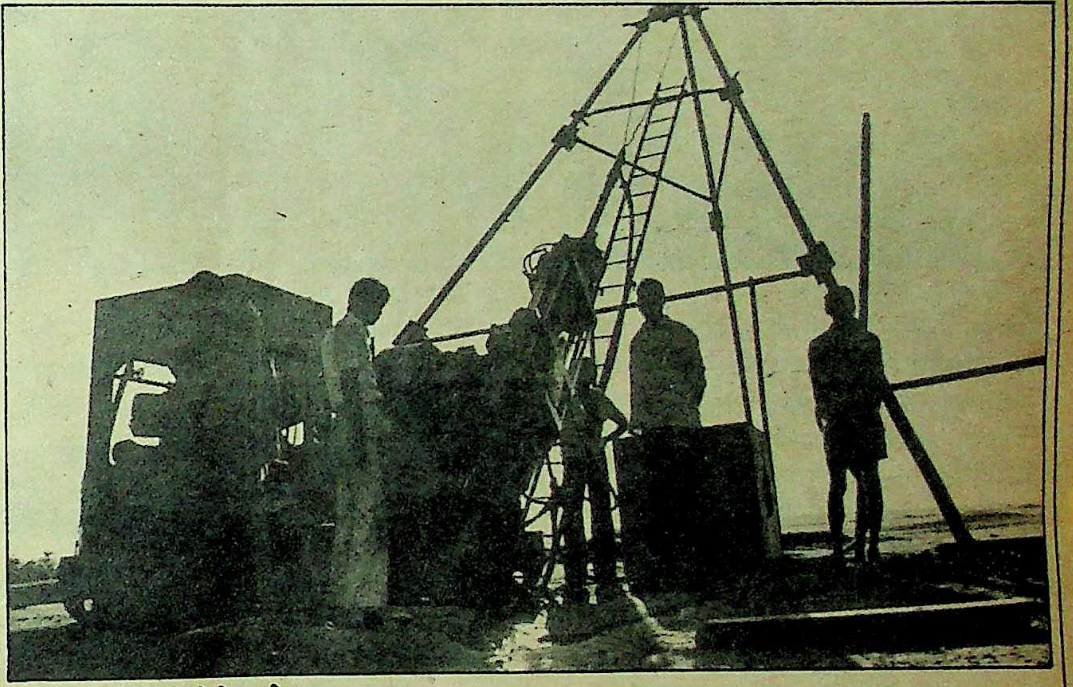

खनन के लिए इकलौती मशीन

बिहार में सोने के अकूत खजाने का पता लगाने के सिलसिले में प्रदेश का खनन एवं भूतत्व विभाग जिस तरह के प्रहसन कर रहा है, वह सचमुच दिलचस्प है। खनन एवं भूतत्व के मुलाजिम १९८२ से ही मुंगेर जिले के जमुई अनुमंडल के करमटिया क्षेत्र में सोने की संभावनाएं संजोये बैठे हैं, पर न उनके पास उपयुक्त खुदाई की मशीनें ही हैं और न पर्याप्त मजदूर। इस स्वर्ण खनिज अन्वेषण परियोजना में मजदूर से लेकर अधिकारियों की संख्या सिर्फ बारह है। इनमें नौ मजदूर और तीन अधिकारी हैं। बस इसी नन्ही सी फौज से बेशकीमती सोने के भंडार की शिनाख्त का काम चल रहा है।

झाझा स्टेशन से कुछ दूर सोनो प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन ८ किलोमीटर की दूरी पर करमटिया क्षेत्र है जो अबरक बहुल क्षेत्र का उत्तर-पूर्व हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से करमटिया के इर्द-गिर्द का क्षेत्र समतल परत की पूर्वी शाखा है। यहां सोने का खनिज सल्फ्यूरिक प्रकृति का है। पायराइट्स आर्सेनपाय्राइट्स आदि के तत्व भी इसमें पाये जाने के संकेत हैं।

सबसे पहले करमटिया के निकटवर्ती गांव चुरहैत के एक मुसहर विदेशी मांझी को यहां आम के वृक्ष के समीप सोने का कुछ अंश मिला। उसने उस पीली धातु को पहले पीतल समझा। पर बाद में उसे पता लगा कि यह तो सोने का बुरादा है। वह बुरादा उसने सोनार के हाथों ढाई हजार में बेचा। फिर तो आसपास के ग्रामीणों में सोना हासिल करने की होड़ सी मच गयी। सरकार को भी इसी होड़ और हलचल के बाद जानकारी मिली। बस खनन एवं भूतत्व विभाग आनन-फानन में अपने हल्के-फुल्के लाव-लश्कर और चंद मजदूरों सहित यहां आ पहुंचा। विदेशी मांझी को जिस आम के वृक्ष के निकट सोना पहली बार मिला था, उसका सुंदर

सोने के महत्व से बेखबर : अजय कुमार

नमूने के लिए: अयस्क सोना

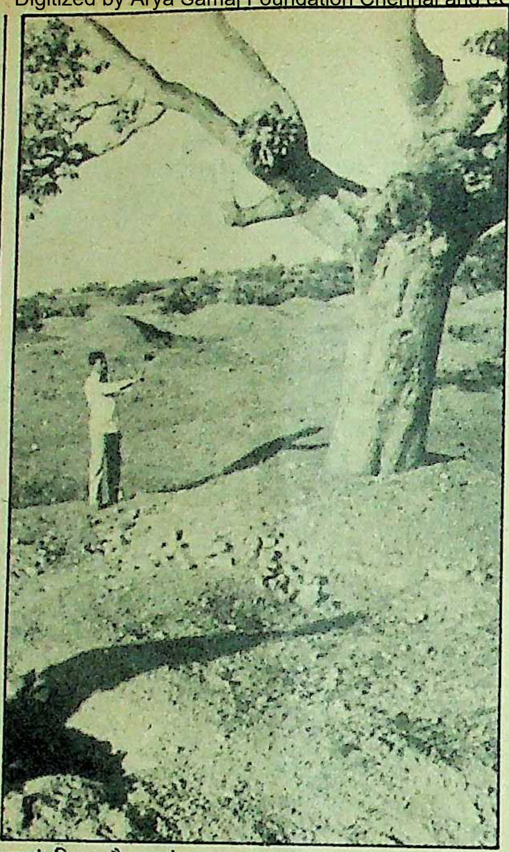

यहां छिपा है कारूं का खजाना

नामकरण भूतत्व विभाग के अधिकारियों ने कर दिया—गोल्डेन ट्री। बस ऐसी ही चंद काल्पनिक खुशफहमियों को गढ़कर साधनहीन भूतत्व विभाग के एक-दो अधिकारी अपनी नौकरी कर रहे हैं। खनन कार्य करने के लिए यहां बस ले-देकर एक ही मशीन है। वह भी सिर्फ दो साल पहले सुलभ करायी गयी थी। यहां तैनात कर्मचारियों का कहना है कि यह इकलौती 'ड्रीलिंग मशीन' ५०० मीटर गहरे तक खुदाई कर सकती है।

अपर्याप्त साधन: काशी मांझी विगत तीन-चार वर्षों से कारूं के इस संभावित खजाने की खुदाई में बतौर मजदूर कार्यरत हैं। काशी कहते हैं कि उन्हें खनन के दौरान कई बार सोने के कण मिल चुके हैं। प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर बैकुंठ सिंह को भी पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन सोना यहां मिलकर रहेगा। पर दूसरी तरफ मजदूर बालदेव यादव इन संभावनाओं को नकारते हुए कहते हैं कि पिछले तीन वर्षों से मैं यहां काम कर रहा हूं, पर आज तक कहीं सोने का बुरादा नहीं मिला। वह कहते हैं कि मुझे सोने से नहीं अपनी मजदूरी से मतलब है। सोना मिले न मिले। 'स्वर्ण खनिज अन्वेषण परियोजना' का सारा दारोमदार अजय कुमार पर है जो मुंगेर जिला भूतात्विक कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर हैं। अजय खुद इस धातु के विशेषज्ञ नहीं हैं, पर नौकरी करनी है, तो सोना क्या हीरे-खोजने को कहा जायेगा, तो वह भी करना पड़ेगा। अजय के पूर्व इस प्रोजेक्ट को एन०एन० संडवार संभाल रहे थे। पूरे प्रोजेक्ट की मैपिंग उन्होंने ही की थी। पहले चरण में माइका शिस्ट, एंफी बोलाइट और क्वार्ट्स आदि मिले। अजय कुमार कहते हैं कि सर्वप्रथम खुदाई से अयस्क संकलन का कार्य चल रहा है। फिर उस अयस्क का अध्ययन किया जायेगा कि सचमुच इस क्षेत्र में सोना भंडार है भी या नहीं। अजय कहते हैं कि अकेले बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग से इस पूरी परियोजना को सफल करना संभव नहीं। इसके लिए भारत सरकार के भूतत्व सर्वेक्षण विभाग को भी हाथ बंटाने के लिए उतरना होगा। अयस्क संकलन के बाद उसे परीक्षण के लिए कोलार गोल्ड माइंस भेजा जायेगा।

एक और दावा: सिर्फ करमटिया क्षेत्र में ही सोने के भंडार का पता लगाने का यह 'ड्रामा' नही चल रहा, बल्कि रांची जिले के तमाड़ इलाके में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तमाड़ इलाके में एक नदी है करकी। सरकारी अमले-कफले यह दावा बार-बार कर चुके हैं कि इस नदी के निकट सोने की कीमती परत है। पर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तमाड़ क्षेत्र के निकट लोहड़ी के हिस्से में प्रोजेक्ट का प्रारूप आदि भी तैयार है, पर नतीजा क्या होगा यह शायद बताने की जरूरत नहीं।

यों देश के पूर्व-मध्य भाग में सोना कम पाया गया है। सोने का भंडार देश में बस तीन इलाकों कोलार, हट्टी और रामगिरी के इलाके में है। अब देखना है कि बिहार में भूतत्व खनन विभाग का यह खेल कितना कामयाब होता है। खनन भूतत्व राज्यमंत्री ओमप्रकाश लाल दावा करते हैं कि इस परियोजना में कामयाबी मिलेगी। लाल ने 'माया' को बताया, "अभी तो परियोजना प्रथम चरण में ही है। थोड़ा धैर्य रखना होगा।"

—विकास कुमार झा

छाया: प्रभाकर

सिर्फ करमटिया क्षेत्र में ही सोने के भंडार का पता लगाने का यह 'ड्रामा' नहीं चल रहा, बल्कि रांची जिले के तमाड़ इलाके में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तमाड़ इलाके में एक नदी है करकी। सरकारी अमले-कफले यह दावा बार-बार कर चुके हैं कि इस नदी के निकट सोने की कीमती परत है। पर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है।

विकास
गाइड बुक
1988

इण्टर,हाईस्कूल व जू.हाईस्कूल परीक्षा-1988
सर्वश्रेष्ठ व एकमात्र परीक्षा पथ प्रदर्शक.....
विकास गाइड बुक
* केवल सम्भावित (Expected) प्रश्नों का समावेश
* पूर्ण पाठ्यक्रम पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में लिखित
* हर एक विषय पर अलग-अलग उपलब्ध
* प्रत्येक पृष्ठ पर वर्ष '1988 मुद्रित
इनामी प्रलोभनों से दूर रहें
विकास बुक एजेंसी, आगरा
MEHRA
V.5

मेरठ कमिश्नरी का घेराव

वीर बहादुर पर टिकैत का एक और हमला

किसानों के एकछत्र नेता: टिकैत

महेंद्र सिंह टिकैत ने मेरठ में लाखों लोगों को एकत्र करके एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसान उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक शक्ति बन गये हैं। इस शक्ति ने प्रदेश सरकार के वर्तमान और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के सामने खतरा खड़ा कर दिया है। प्रांतीय इंका नेतृत्व और इंका आलाकमान इस खतरे का सामना करने के लिए क्या रणनीति अपना रहा है? क्या टिकैत अपराजेय बनते जा रहे हैं?

किसान नेता चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न तो राजीव गांधी की कोई सरकार है और न ही वीर बहादुर सिंह का शासन। पिछले १५ महीनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग के बेताज बादशाह बने महेन्द्र सिंह टिकैत ने गत वर्ष ११ अगस्त को अपने गांव सिसौली (मुजफ्फरनगर) में कई लाख किसानों के सामने वीर बहादुर सिंह को बुरी तरह अपमानित कर खुले आम यह ऐलान किया था, "देखें, किसमें हिम्मत है, जो हमसे टैक्स वसूल ले और इस इलाके में सरकार चला ले।"

११ अगस्त की इस घटना के बाद टिकैत को जहां अपनी असली ताकत का पता चल गया था, वहीं अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीर बहादुर सिंह भीतर-ही-भीतर रणनीति तैयार करने में जुट गये थे। इसी रणनीति के तहत १९ अक्तूबर को टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में मेरठ मंडल के इंकाइयों की रैली आयोजित की गयी। यह टिकैत और वीर बहादुर सिंह के बीच शक्ति परीक्षण का असली मौका था, क्योंकि टिकैत ने घोषणा कर दी थी, "हम इस रैली को किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के लोग मुजफ्फरनगर जानेवाली सभी सड़कें जाम कर देंगे तथा किसी भी मंत्री या नेता को शहर में घुसने नहीं दिया जायेगा।"

टिकैत की इस धमकी से पहले तो इंकाइयों के हाथ-पैर फूल गये, किन्तु बाद में वीर बहादुर सिंह ने अपनी रणनीति के तहत मुजफ्फरनगर के शक्तिशाली नेता विद्या भूषण पर रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। नतीजतन, विद्या भूषण ने गांव-गाव के 'नामी-गिरामी' लोगों को टिकैत और उनके साथियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यही नहीं किसान यूनियन के एक प्रभावशाली नेता तथा टिकैत के समधी चौधरी सुखवीर सिंह को 'तोड़कर' टिकैत के मुकाबले में खड़ा कर दिया गया। टिकैत इस रणनीति को समझ गये। वह विद्या भूषण के 'लट्ठबाजों' का मुकाबला नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना विरोध वापस लेते हुए कहा, "हम किसानों को मारपीट से दूर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश भी पंजाब बन जाये, इसलिए रैली में जानेवाले लोगों को बलात् रोकने का निर्णय किसान यूनियन वापस लेती है।" लेकिन इसी के साथ टिकैत ने यह भी ऐलान कर दिया था, "जो किसान कांग्रेस की रैली में शामिल होगा, वह 'गद्दार' माना जायेगा। हम उसे अपनी यूनियन से निकाल देंगे।"

इस सबके बावजूद वीर बहादुर सिंह रैली को सफल बनाने में कामयाब हो गये थे। उसी के बाद से टिकैत, वीर बहादुर सिंह को 'मजा चखाने' का मौका ढूंढ़ने लगे थे। अंततः यह मौका उन्हें तीन महीने बाद मिल ही गया। टिकैत ने घोषणा कर दी, "भारतीय किसान यूनियन अपनी ३५ सूत्रीय मांगों को लेकर २७ जनवरी को मेरठ मंडल के आयुक्त का घेराव करेगी।"

किसान यूनियन की इन मांगों में ज्यादातर बिजली विभाग से संबंधित थीं। अन्य मांगों में गन्ना पेराई के लिए कोल्हुओं पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाने, किसानों के भूमि-अधिग्रहण के मामले में पर्याप्त मुआवजा देने, चकबंदी संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करने, चौगामा नहर की खुदाई कार्य तेज करने, जैसी मांगें थीं।

मेरठ के जिला प्रशासन को उम्मीद थी कि इस घेराव के लिए मुश्किल से १०-१५ हजार किसान ही कमिश्नर-कार्यालय पर पहुंचेंगे। लेकिन २२ जनवरी तक इंटलीजेन्स विभाग के लोगों ने गांव-गांव में घूमकर जो रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया था कि करीब एक लाख किसानों की भीड़ २७ जनवरी को मेरठ में इकट्ठी हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद वीर बहादुर सिंह ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया।

२४ जनवरी को उन्होंने मेरठ मंडल के आयुक्त विजय कुमार दीवान और पुलिस उप-महानिरीक्षक श्रीराम अरुण को दिल्ली स्थित यू०पी० भवन में तलब किया। इन दोनों अफसरों को उन्होंने आदेश दिया, "किसानों की इस भीड़ को जैसे भी हो, रोका जाये और अगर टिकैत नहीं मानते, तो उन्हें 'रासुका' में गिरफ्तार कर लिया जाये।"

शव की राजनीति: आंदोलन के दौरान मरे किसान का शव

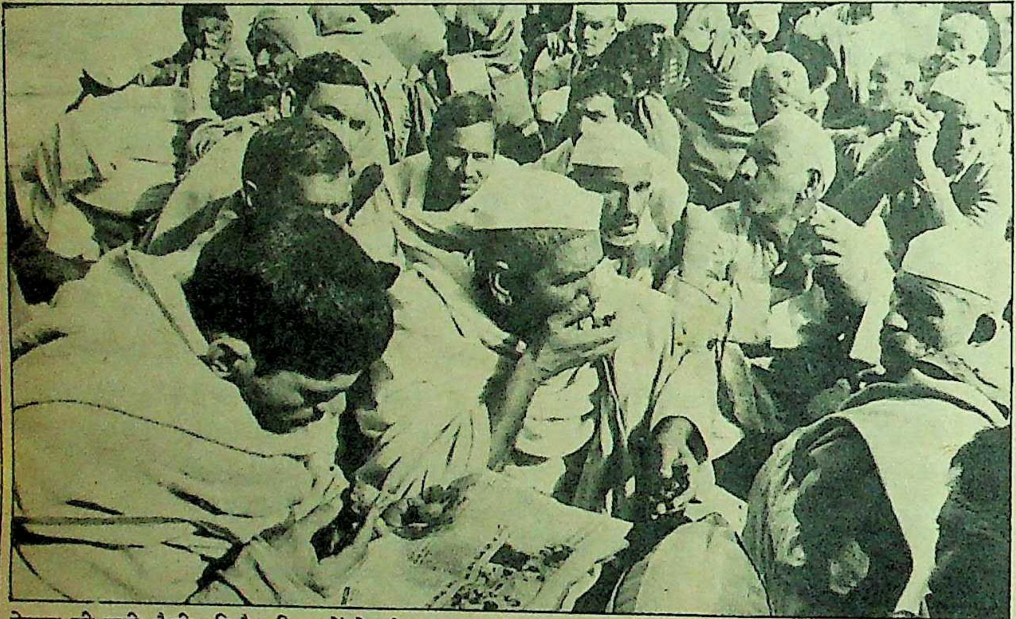

नेतृत्व की नयी शैली: टिकैत किसानों के बीच

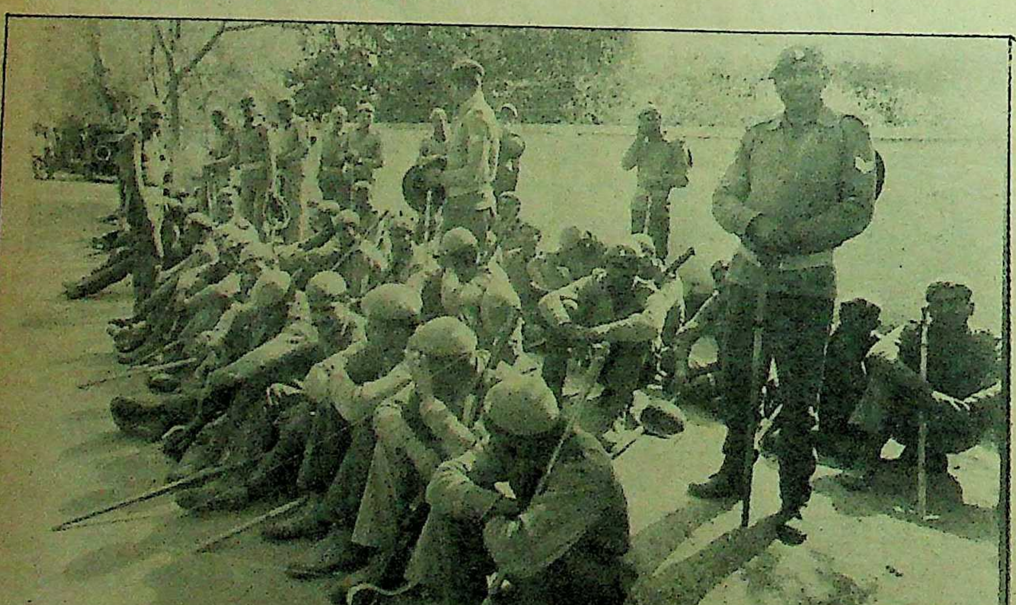

जनशक्ति को दबाने के लिए सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन

प्रशासन की तैयारी: अगले ही दिन यानी २५ जनवरी से मेरठ शहर में धारा १४४ लगा दी गयी। इसका आधिकारिक कारण यह बताया गया कि कुछ अवांछनीय तत्व मेरठ में अशान्ति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आदेश के तहत लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर चलना ही नहीं, नारे लगाने तक पर पाबंदी लगा दी गयी थी। मेरठ के अतिरिक्त जिलाधिकारी सुभाष सक्सेना ने इसी तरह का एक और आदेश जारी कर २६ और २७ जनवरी को शहर में ट्रैक्टर-ट्राली के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला प्रशासन को सबसे बड़ा भय यही था कि अगर किसान ट्रैक्टर-ट्राली लेकर शहर में घुस आयेंगे, तो उन्हें खदेड़ना मुश्किल काम होगा। जिला प्रशासन ने २७ और २८ जनवरी को सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी की भी घोषणा कर दी। किसानों को शहर में घुसने से रोकने के लिए आसपास के जिलों से पी०ए०सी० की ३० कम्पनियां बुला ली गयीं। करीब दो सौ महिला पुलिस-कर्मियों को भी तैयार रहने को कह दिया गया। २७ जनवरी के लिए दिल्ली से केन्द्रीय पुलिस बल भेजे जाने की भी मांग की गयी।

इसी बीच जिला प्रशासन ने अपने कुछ बिचौलियों के माध्यम से टिकैत को कमिश्नर के कार्यालय का घेराव न करने के लिए मनाने की भी कोशिश की। इन बिचौलियों ने टिकैत को समझाया कि यूनियन की मांगें मानना कमिश्नर के बूते के बाहर है, इसलिए अगर घेराव करना है, तो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री का करो, लेकिन टिकैत अपनी जिद पर अडे रहे। वह बोले, "मैं अपने ऐलान से कभी पीछे नहीं हटता। कमिश्नर का घेराव तो होकर ही रहेगा।"

मेरठ के जिलाधिकारी विजय कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने तब टिकैत की गिरफ्तारी का निर्णय ले लिया। २५ जनवरी को ही उन्हें पता चला कि टिकैत बडौत के पास रमाला गांव में किसानों की सभा कर रहे हैं। यह खबर मिलते ही डी०एम० और एस०एस०पी० भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर रमाला गांव जा पहुंचे। सभा में मौजूद किसानों को जब यह पता चला कि पुलिस उनके नेता को गिरफ्तार करने आयी है, तो तमाम किसान अपने लाइसेन्सी हथियार लेकर मकान की छतों पर चढ़ गये तथा पुलिस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली। इसी बीच किसान यूनियन का रणसिंघा बज गया। बस फिर क्या था, देखते-ही-देखते कई हजार किसानों की भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। डी०एम० और एस०एस०पी० भाग खड़े हुए। अपने अफसरों को भागा देख पुलिस के जवान भी टिकैत से क्षमा-याचना करते हुए वापस लौट गयें। (देखिए बाक्स)

इस घटना ने आग में घी का काम किया। यही वजह थी कि २६ जनवरी की शाम से ही किसानों की भारी भीड़ मेरठ में इकट्ठा होने लगी। जहां जिला प्रशासन को १५-२० हजार किसानों के आने की उम्मीद थी, वहीं २७ जनवरी की सुबह तक मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर,

बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि जिलों के डेढ़ लाख से ज्यादा किसान मेरठ जा पहुंचे। यही नहीं उत्तर प्रदेश से सटे हरियाणा के जिलों से भी भारी संख्या में किसान धरना देने आ गये।

प्रशासन ने घुटने टेके: किसानों की इस भीड़ ने सरकार और प्रशासन की सभी चौकसियों को धता बता दिया। धारा-१४४ की पाबंदियों का मखौल उड़ाते हुए किसानों के जत्थे बुलंद हौसलों के साथ शहर में घुस आये। परेशानहाल जिला प्रशासन ने २७ जनवरी की सुबह टिकैत के सामने घुटने टेक दिये। कमिश्नर दफ्तर के पास ही सी०डी०ए० मैदान में किसानों को सभा की अनुमति दे दी गयी।

सभा दोपहर दो बजे शुरू होनी थी। उसके बाद से धरना कार्यक्रम था। लेकिन टिकैत काफी देर से करीब पांच बजे सभा-स्थल पर पहुंचे। वह अपने गांव सिसौली से एक बस पर सवार होकर आये थे। उनके साथ करीब २५ हजार किसानों का काफिला था। अपने नेता की 'हिफाजत' के लिए करीब एक दर्जन बन्दूकधारी टिकैत के चारों ओर घेरा डाले हुए थे। बाकी सभी किसान निहत्थे थे। ज्यादातर किसान नारे लगा रहे थे, 'वीर बहादुर कैसा है, गोरखपुर का भैंसा है', 'तख्त बदल दो, ताज बदल दो-बेईमानों का राज बदल दो,' 'जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।

किसानों की इस भीड़ में महिलाएं, नौजवान, बूढ़े और बच्चे सभी थे। टिकैत की यह पहली सभा थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आयी थीं। मंच पर पहुंचकर टिकैत ने कहा, "हम यहां भाषण करने नहीं, धरना देने आये हैं। कमिश्नर हमारे बीच आकर मांगों पर बात करें। हम उन्हें एक घंटे की मोहलत देते हैं।" एक घंटा बीत जाने के बाद भी जब कमिश्नर सभास्थल पर नहीं आये, तो टिकैत ने ऐलान किया, "सब लोग बैठकर शान्तिपूर्वक धरना दें। कमिश्नर का घेराव करना है या नहीं करना है, इस बारे में मैं कल बताऊंगा।"

समझौते की कोशिशें: इस अल्टीमेटम के बाद अपर जिलाधिकारी सुभाष सक्सेना सभास्थल पर आये और बोले, "कमिश्नर साहब पांच किसानों के प्रतिनिधि मंडल से अपने दफ्तर में बात करना चाहते हैं, लेकिन टिकैत अड़ गये, "कमिश्नर खुद यहां आकर बात करें।"

सारी रात टिकैत को मनाने का प्रयास जिला प्रशासन करता रहा, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहें उनका कहना था, "कमिश्नर हमारा नौकर है, उसे हमारे बीच आना होगा।" कमिश्नर ने रात्रि में ही हाटलाइन पर लखनऊ में वीर बहादुर सिंह से सम्पर्क कर सारी स्थिति बताते हुए पूछा, "सर, हालत खराब है, क्या किया जाये?"

'तुम्हें किसानों के बीच नहीं जाना है'—मुख्यमंत्री का आदेश हुआ।

उधर दिल्ली दरबार तक यह खबर पहुंची, तो वहां से लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को फोन पर कहा गया, "आप कोई रास्ता निकालें, क्योंकि टिकैत आपकी बात मानता है।"

ऐसे फेल हुआ-'आपरेशन टिकैत'

२३ जनवरी, १९८८ को वीर बहादुर सिंह ने मेरठ के कमिश्नर वी०के० दीवान और उपमहानिरीक्षक राम अरुण को दिल्ली के यू०पी० निवास में बुलाकर पूछा था, "टिकैत को कैसे ठीक किया जाये?" दोनों अफसरों का कहना था, "टिकैत का किसानों में अब वह प्रभाव नहीं रहा है, जो पहले था। अगर हम २७ जनवरी से पहले ही टिकैत को गिरफ्तार कर लें, तो संगठन के दूसरे लोग भयभीत हो जायेंगे और हमारा सिरदर्द भी दूर हो जायेगा।"

उस समय गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित और कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह भी मुख्यमंत्री के पास मौजूद थे। गृहमंत्री तो पूरी तरह चाहते थे कि टिकैत गिरफ्तार कर लिये जायें, लेकिन नरेन्द्र सिंह का कहना था, "इस मामले में जल्दबाजी से खेल बिगड़ सकता है।" मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने नरेन्द्र सिंह को नजरंदाज करते हुए अधिकारियों को हरी झंडी दिखा दी। २४ जनवरी की रात्रि मेरठ में जिला-प्रशासन के अधिकारियों की आपात बैठक हुई। इसी बैठक में 'आपरेशन टिकैत' की योजना बनायी गयी। बैठक में मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और पुलिस-अधीक्षक को भी बुलाया गया था। मुजफ्फरनगर के पुलिस-अधीक्षक एस०एन० सिंह 'आपरेशन टिकैत' से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि यदि टिकैत को गिरफ्तार किया गया, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अपने कथन को बल देने के लिए पुलिस-अधीक्षक इन्टेलीजेन्स विभाग की रपटों का हवाला दे रहे थे। लेकिन उनके तर्क को यह कहकर टाल दिया गया, "जब ऊपर से गिरफ्तार करने के आदेश हैं, तो हमें माथा-पच्ची करने से क्या फायदा?"

२५ जनवरी को टिकैत को बड़ौत से दस किलोमीटर दूर रमाला गांव पहुंचना था। वहां उन्होंने अपने समधी सुखवीर सिंह से समझौते के लिए पंचायत बुलायी थी। तय समय पर टिकैत एक जत्थे के साथ रमाला पहुंचे। वहां पंचायत हुई। लेकिन सुखवीर सिंह ने यह कहते हुए समझौता करने से इनकार कर दिया, "तुम इंका के एजेंट हो।" पंचायत बिना किसी फैसले के समाप्त हो गयी। वहां से टिकैत, एक विशेष आमंत्रण पर जाट नेता तथा लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि पुलिस और पी०ए०सी० के करीब दो सौ जवानों ने रमाला गांव की घेराबंदी कर ली है। इस फोर्स के साथ मेरठ और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारी भी हैं। इसकी सुगबुगाहट गांव में फैली, तो किसानों ने छतों पर चढ़कर मोर्चाबंदी कर ली।

देखते-ही-देखते चारों ओर यह खबर फैल गयी कि पी०ए०सी० के जवानों ने टिकैत को घसीट कर ट्रक में डाल दिया है। कुछ किसानों ने रणसिंघा बजा दिया। बस फिर क्या था हजारों लोग डंडा, लाठी, ईंटा और पत्थर लेकर चारों तरफ से टूट पड़े। हर तरफ से आवाज आ रही थी, 'पुलिसवालों के ट्रक जला दो', 'कोई बचकर न जाने पाये।' इसी के साथ पी०ए०सी० और पुलिस पथराव शुरू हो गया। तब तक टिकैत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। पुलिस पर पथराव की खबर रमाला चीनी मिल के गेस्ट हाउस में बैठे अफसरों को लगी, तो उन्होंने 'फोर्स' को वापस बुला लिया। किन्तु टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह फैलती रही। रात्रि १२ बजे तक हथियारबंद किसान ट्रैक्टरों से आते रहे। टिकैत के गांव सिसौली से ही रात्रि १० बजे तक चार हजार किसान इकट्ठे हुए, जो वीर बहादुर की सरकार की ईंट-से-ईंट बजा देने के लिए दांत किटकिटाते रहे। अपने नेता को सुरक्षित जान वे लोग रात्रि दो बजे के बाद वापस हुए।

उसी शाम टिकैत दिल्ली में जाखड़ के यहां जा पहुंचे। उनके साथ किसान यूनियन के सचिव हरपाल सिंह तथा तीन अन्य लोग थे। पहुंचते ही टिकैत ने जाखड़ साहब को आड़े हाथों लिया, "एक ओर आप समझौते की बात कराते हैं। उधर वीर बहादुर हमें गिरफ्तार करा रहा है।" जाखड़ साहब ने किसी तरह टिकैत को ठण्डा किया, "मैं अभी वीर बहादुर को बुलवाकर तुम्हारे सामने बात करता हूं।"

जाखड़ साहब ने यू०पी० निवास फोनकर वीर बहादुर को तलब किया। वीर बहादुर फौरन गोपीनाथ दीक्षित के साथ जाखड़ साहब के घर हाजिर हो गये। मुख्यमंत्री को देखते ही टिकैत आग बबूला हो गये। वीर बहादुर बस मुस्करा कर रह गये। जाखड़ साहब ने अलग कमरे में वीर बहादुर से पांच-सात मिनट तक बात की। फिर टिकैत को पास बिठाकर वार्ता की। टिकैत २७ जनवरी का प्रस्तावित धरना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं हुए। टिकैत का कहना था, "ऐसा करने पर लोग मेरी टोपी उछालेंगे।"

"तो फिर आप भविष्य में 'अपोजीशन' से कोई तालमेल न करें। मेरी सरकार हमेशा आपके सम्मान की रक्षा करेगी," वीर बहादुर ने टिकैत को समझाया।

—लखनऊ ब्यूरो

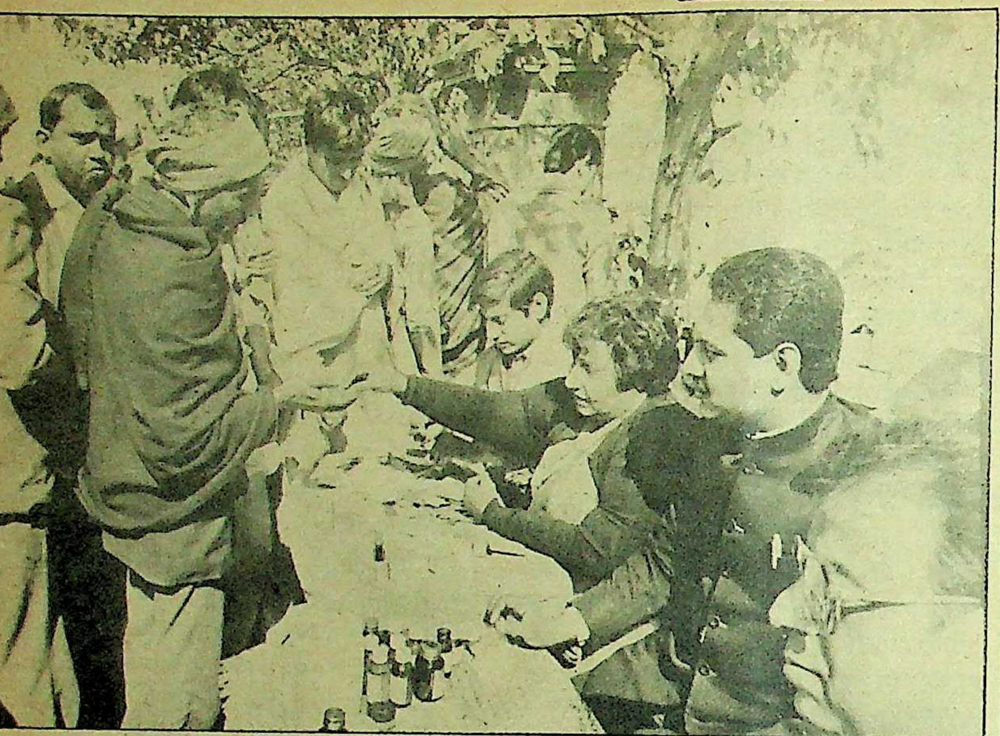

जनता की सोत्साह भागीदारी : धरने के दौरान मुफ्त दवा वितरण

जाखड़ से टिकैत के पुराने संबंध हैं। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। यही वजह है कि जाखड़ शुरू से ही टिकैत के किसान आन्दोलन से सहानुभूति रखते हैं। वह वीर बहादुर सिंह को किसान विरोधी मानते हैं। दिल्ली दरबार के निर्देश पर ही वीर बहादुर सिंह अपने गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित और कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह के साथ जाखड़ से मिले। वीर बहादुर सिंह इस बात के लिए तैयार हो गये कि ३५ सूत्रीय मांगों में जो गैरवित्तीय मांगे हैं, उन्हें तत्काल स्वीकार कर लिया जायेगा। किसानों की कर्ज और लगानमाफी जैसी वित्तीय मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं है, लेकिन वीर बहादुर द्वारा टिकैत को गिरफ्तार कराने की कोशिश के कारण जाखड़ ने समझौता प्रयास से हाथ खींच लिया और विदेश चले गये।

कमिश्नर कार्यालय का घेराव : २६ जनवरी को किसानों की भीड़ और भी बढ़ गयी थी। इस दौरान कमिश्नर का कार्यालय भी घेर लिया गया। घेराव से पूर्व ही कमिश्नर वी०के० दीवान अपने परिवार सहित दूसरी जगह चले गये। उधर सभा-स्थल सी०डी०ए०मैदान और कमिश्नर कार्यालय के बाहर किसान नेताओं के लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर दी। २६ जनवरी को टिकैत ने एक मैदान जीत लिया। किसान यूनियन के एक प्रमुख नेता तथा टिकैत के समधी सुखवीर सिंह भी कई हजार किसानों के साथ धरने पर आ बैठे। सुखवीर सिंह अभी तक टिकैत के सबसे बड़े विरोधी थे। वह यह आरोप लगा चुके थे कि टिकैत यूनियन के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन धरना आन्दोलन में शामिल होकर सुखवीर सिंह ने कहा, "मैं बीमार था। इसी वजह से धरने में तय समय पर शरीक नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि किसान तीन दिन से कमिश्नरी के बाहर हाड़ कंपा देनेवाली ठंड में बैठे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। चारपाई छोड़कर आपके बीच आ गया हूं। इसी के साथ उन्होंने टिकैत से अपने सारे मनमुटाव समाप्त करने का भी ऐलान कर दिया। सुखवीर सिंह ने कमिश्नर-दफ्तर के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया।

इसी बीच कमिश्नर ने परगना अधिकारी दिलबाग सिंह को टिकैत के पास भेजकर कहलाया कि यूनियन की ३५ में से १३ मांगें मान ली गयी हैं। ये सभी गैरवित्तीय मांगे थीं, लेकिन जब परगना-अधिकारी से टिकैत ने कमिश्नर का लिखित आश्वासन मांगा, तो उसने लिखित में कुछ भी देने से इनकार कर दिया।

टिकैत की ललकार : बस इसी के बाद टिकैत ने ऐलान कर दिया, "हमारा यह धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक यूनियन की पांच प्रमुख मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किये जाने की सूचना कोई मंत्री हमारे बीच उपस्थित होकर नही देगा।"

ये पांच मांगे थीं—छह माह का बिजली का बिल और लगान माफ किया जाये। गन्ने का मूल्य ३५ रुपए क्विन्टल निर्धारित हो। खाद का मूल्य ३० रुपए क्विन्टल घटाया जाये तथा किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमें वापस लिये जायें।

टिकैत का कहना है, "मुख्यमंत्री किसानों की मांग यह कहकर ठुकरा रहे हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन उनका बेटा जब भी चाहे सरकारी हेलीकाप्टर पर देहरादून से दिल्ली आता-जाता है। मुख्यमंत्री अपने बेटे को दून स्कूल में पढ़ा रहा है। अपनी बेटी का रिश्ता मुजफ्फरनगर के एक आई०ए०एस० लड़के से तय कर दिया है। गांव में रस्म के मौके पर मुख्यमंत्री चार हेलीकाप्टर लेकर गया था। आखिर मैं पूछता हूं कि इस फिजूलखर्ची के लिए पैसा कहां से आता है। हम किसान हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। अहंकारी का हमेशा सर्वनाश हुआ है। हम किसी की बेइज्जती या 'पोजीशन' खराब नही करना चाहते। लेकिन, अगर किसान के मान-सम्मान का सवाल खड़ा हुआ, तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी किसानों के बीच आना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि वीर बहादुर किसान का बेटा नहीं है। उसे किसानों से नफरत है। नहीं तो क्या वजह है कि एक मंदिर का उद्घाटन करने वीर बहादुर मुजफ्फरनगर आ सकता है, लेकिन किसानों की पंचायत में अपनी बात कहने मेरठ नहीं आ सकता।"

इस बेमियादी धरना आन्दोलन में किसानों की भीड दिन-प्रतिदिन बढ़ती गयी। समय और दिन बीतने के साथ-साथ किसानों के हौसले और बुलंद होते गये। शहर के आसपास के गांवों से ट्रैक्टरों में भरकर उनके लिए खाना आता रहा। शहर की कई संस्थाओं ने धरने पर बैठे किसानों के लिए नियमित रूप से भुने चने और गुड की व्यवस्था कर दी। लेकिन ३० जनवरी की भोर धरने पर बैठे एक ५० वर्षीय किसान भगवान सिंह (बिजनौर निवासी) की ठण्ड लग जाने से मृत्यु हो गयी व सात अन्य किसान भी ठण्ड की वजह से सख्त बीमार पड़ गये।

इसी के बाद टिकैत ने घोषणा कर दी, "किसान अब गोला बारूद से नहीं डरेंगे। हमारी लड़ाई आर-पार होगी। शहीद भगवान सिंह का शव भी अब यहां से तभी हटेगा, जब हम हटेंगे। उनका स्मारक भी इसी स्थान पर बनेगा।"

टिकैत के इस ऐलान के बाद अफसरों के हाथ-पैर फूल गये। घटनास्थल पर प्रशासन की ओर से आनन-फानन अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी। बीमार किसानों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घटनास्थल पर ही एक अस्थाई चिकित्सालय स्थापित कर दिया गया।

अभी तक घमंड में चूर जो अफसर यह कह रहे थे कि वे किसानों के बीच नहीं जायेंगे, उन्हें किसानों के दृढ़ रुख के सामने झुकना पड़ा। अन्ततः कमिश्नर को टिकैत के पास यह कहलाना पड़ा, "यूनियन की पांचों प्रमुख मांगों का सबंध राज्य सरकार से है। इन्हें स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है।" कमिश्नर के इस बयान पर टिकैत बोले, "सरकार है कहां, हमें यही बता दे। हम वहीं पहुच जायेंगे। मेरठ आये, तो कमिश्नर छिप गया। लखनऊ जाऊंगा, तो मुख्यमंत्री गायब हो जायेगा। दिल्ली पहुंचूंगा, तो प्रधानमंत्री सामने नहीं आयेगा।" इसी के बाद धरना-स्थल को घेरे खड़े पी०ए०सी० के जवानों ने शहीद भगवान सिंह के शव के संमक्ष अपनी राइफलें नीची कर शोक सलामी दी। पहली बार जनता को नजरंदाज करनेवाली नौकरशाही को किसान के रुतबे का अहसास हुआ।

३१ जनवरी को तो धरने पर बैठे किसानों की भीड़ ढाई लाख तक पहुंच गयी थी। किसानों के समर्थन में छात्र, वकील और बुद्धिजीवी भी धरने में शामिल हो गये। पहली फरवरी से तो विभिन्न

प्रदेशों के किसान भी मेरठ पहुंचने लगे थे। पंजाब किसान यूनियन के संस्थापक भूपेन्द्र मान, बिहार के किसान नेता आर०पी० वर्मा, हरियाणा के श्री दैहया हजारों किसानों के साथ महेन्द्र सिह टिकैत का साथ देने मेरठ जा पहुंचे। यही नहीं शेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी, बंधुआ मुक्ति मोर्चे के नेता स्वामी अग्निवेश तथा प्रसिद्ध किसान नेता अनिल गोटे भी टिकैत के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए मेरठ पहुंच गये। लेकिन इस सबके बावजूद वीर बहादुर के खास सिपहसालार गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने ३१ जनवरी को कानपुर में सार्वजनिक रूप से यह कहकर समझौते के रास्ते बंद कर दिये, "महेन्द्र सिह टिकैत बहुत उड़ रहे हैं, उन्हें ठीक कर दिया जायेगा।"

आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामोण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी है। किसानों को सिचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। नलकूपों की खराबी को ठीक नहीं किया जा सका। यही नहीं, बीज और खाद भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब यह स्थिति होगी तब फिर भला किसानो को आन्दोलन करने से कैसे रोका जा सकेगा। इन स्थितियों का फायदा चौधरी महेन्द्र सिह टिकैत को मिल रहा है और आज वह राज्य सरकार के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने खड़े हो गये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान में अब और अधिक देरी न करे, यथाशीघ्र ही कुछ ऐसे कदम उठाये, जिससे किसानो को राहत मिल सके। यह निश्चित है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो किसानों का यह आन्दोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। जो समस्याएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की हैं, वही समस्याएं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के किसानों की भी हैं। आखिर कब तक किसानों की समस्याओं को हल करने के बयान दिये जाते रहेंगे। किसानों को अब केवल भाषणों से संतोष नही होगा। वे तो कुछ ऐसे कदमों की प्रतीक्षा में हैं, जिनसे उन्हें वास्तव में राहत मिल सके।

अपनी ताकत के बल पर वीर बहादुर सिह को पूरी तरह परास्त करने के बाद अब महेन्द्र सिह टिकैत ने दिल्ली पर अपनी निगाह गड़ा दी है। मेरठ में किसान आंदोलन के दौरान टिकैत के आदेश पर जहां किसानों ने दिल्ली को दूध की आपूर्ति बंद कर दी, वहीं दो लाख किसानों ने सर्वसम्मति से अपने नेता को 'महात्मा टिकैत' की उपाधि से अलंकृत कर दिया।

मेरठ में निरंतर कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों की संगठन शक्ति और धैर्य की सीमा को देखकर न केवल उत्तर प्रदेश के इंकाई परेशान हो उठे, वरन राजीव गांधी तक चिंतित हो गये। वीर बहादुर सिह २७ जनवरी से ही दिल्ली में रहकर किसानों के धरने और टिकैत की गतिविधियों की क्षण-प्रतिक्षण जानकारी प्राप्त करते रहे। इस गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए पहली फरवरी को वरिष्ठ इंकाइयों की बैठक दिल्ली में हुई। दो घंटे तक चलने वाली इस बैठक में ज्यादातर इसी बात पर विचार होता रहा कि 'टिकैत को कैसे मनाया जाये ?' इस बैठक में इका महासचिव गुलाम नबी आजाद, प्रादेशिक अध्यक्ष महावीर प्रसाद, वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी, मोहसिना किदवई, ब्रह्मदत्त, शीला दीक्षित, सुशीला रोहतगी, जियाउर्रहमान अंसारी, गोपीनाथ दीक्षित आदि मौजूद थे।

मेरठ में लाखों किसानों को इकट्ठा कर टिकैत ने कई मकसद पूरे कर लिये हैं। उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रतिद्वंद्वी किसान नेता (और अपने संबंधी) चौधरी सुखवीर को शक्तिहीन बनाकर अपना एकछत्र नेतृत्व साबित कर दिया है। शरद जोशी की अपील को ठुकरा कर वह बंगलौर में हुई अखिल भारतीय किसान संगठन संयोजन समिति की बैठक में नहीं गये। रैली की मार्फत उन्होने जता भी दिया कि मैं ही असली किसान नेता हूं। आगामी १२ मार्च को दिल्ली में पचास लाख किसानों की प्रस्तावित रैली से पहले उन्होंने मेरठ कमिश्नरी का घेराव कर अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिये हैं कि शरद जोशी की रैली बिना उनके नहीं हो सकती। जिस तरह से अपने खर्चे पर, रात के लिए गर्म बिस्तरों का और आठ दस दिनों तक के लिए खाने का इंतजाम करके लाखों किसान मेरठ पहुंचे, वह उत्तर प्रदेश सरकार के सिरदर्द के लिए काफी है। पर दो पहलू हैं। जहां एक ओर वीर बहादुर सरकार किसान असंतोष का अपने हक में समाधान करने में असफल रहकर कांग्रेस की भावी पराजय के बीज बो रही है, वहीं टिकैत की मांगें सिर्फ समृद्ध किसानों से ताल्लुक रखती हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन भूमिहीन खेत मजदूरों और छोटे किसानों की लड़ाई नहीं लड़ेगी, तो आज का पासा उसके खिलाफ भी जा सकता है।

—मेरठ से, अजय कुमार

छाया: मनमोहन शर्मा

अनोखी लड़ाई

किसानों की एकता, दृढ़ता, अनुशासन, तहजीब, व्यवस्था और रणसिघों की ताकत का एक और जबरदस्त सबूत किसान नेता महेंद्र सिह टिकैत ने मेरठ के सी०डी०ए० मैदान में दिया। लाखों किसानों और उनसे हमदर्दी रखने वाले सैकड़ों बुद्धिजीवियों और हजारों शहरी नौजवानो पर एक अदद आदमी का वर्चस्व और वह भी किसी जोर जबरदस्ती के बगैर। ऐसा है वह शख्स जिसे किसान महात्माओं की संज्ञा देने लगे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ १८५७ में क्रांति की एक हुंकार उठी थी, जिसमें खून बहा था और हिंसा हुई थी। इस बार फिर मेरठ से हुंकार उठी है, मगर न तो कहीं एक बूंद खून बहा और न ही कोई हिंसा हुई। मेरठ जैसे शहर से किसी ने सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। इस बार अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नहीं, अपनी ही हुकूमत के अन्याय और उपेक्षा के खिलाफ किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है।

धरना पर कड़कती ठंड में खुले आसमान तले बैठे किसानों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं और न ही कोई शिकायत है। बस चमकती निगाहों में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक रोशन जज्बा है। उनका दिल अपने नेता की धड़कन पर धड़कता है। उसकी आवाज पर जान तक देने की तमन्ना है। आखिर मेरठ में ये 'बावले' चाह क्या रहे हैं ? उनका कहना है, "हम वीर बहादुर सरकार को उसका फर्ज याद दिलाना चाहते हैं। एक ऐसा फर्ज जो किसानों के प्रति सरकार और व्यवस्था का होता है।" किसान भीख मांगने नहीं, अपना हक अपने ही शर्तों पर लेने आये हैं। इसीलिए उनकी इस लड़ाई की पैंतरेबाजी और इसका मैदान उनके खुद का मैदान है। एक ओर निहत्थे, पूरी तरह से अनुशासित किसान अहिंसा का हथियार लिये हुए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के आलाबरदार बंदूकों से तने सिपाहियों का सहारा लिये इस इंतजार में हैं कि हिंसा या उकसावे की कोई छोटी-सी घटना हो, तो वह 'अपने तरीके से' लाखों किसानों को 'ठीक कर दें'। मगर किसान अशांति व्यवस्था बनाये रखने का उन्हें बहाना नहीं दे रहे हैं। प्रशासन सहम कर हार मान चुका है और बंदूकधारी सिपाहियों की सहानुभूति अंदर-ही-अंदर सत्याग्रही किसानों की तरफ होती गयी है।

यह अनोखा तरीका सरकार को समझाने के लिए निकाला है—चौधरी महेंद्र सिह टिकैत ने, जो उन्हीं के बीच से निकला एक आम आदमी है। किसानों की भीड़ का औजार है, अहिंसा और हुंकार है रणसिघा। उनका बल है, एकता और उनका संबल है सचाई। आजाद हिंदुस्तान ने लड़ाई के जितने भी तरीके देखे, उनमें टिकैत का यह तरीका अपने एक अलग अंदाज में है।

देश के दूसरे तबके भी इस अनोखी लड़ाई का नतीजा देखने के लिए लालायित हैं। इस नतीजे पर ही मजलूम और आम आदमियों की उम्मीद टिकी है। किसान-शक्ति और संगठन की जीत पर ही अब उसकी जीत निर्भर करती है। पहली बार सड़ी-गली व्यवस्था और उसकी रक्षा करने वाली वर्गीय सरकार को 'किसान-शक्ति' यानी लोकशक्ति का अहसास कराया है टिकैत की इस अनोखी लड़ाई ने।

—अशोक रजनीकर

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर
सेवा

वीर बहादुर विरोधियों को तरजीह : सेवा दल शिविर में जगदम्बिका पाल से राजीव गांधी की गुफ्तगू

फिर शुरू हो गया वीर बहादुर हटाओ अभियान !

राजस्थान में हरिदेव जोशी का पतन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में उन लोगों की हिम्मत बढ़ी है जो वीर बहादुर सिंह हटाओ मुहिम में लगे हैं। ये लोग किन कारणों से दावा कर रहे हैं कि वीर बहादुर सिंह राजीव गांधी की नजरों से गिर चुके हैं ?

राजस्थान में हरिदेव जोशी को हटाकर उनके स्थान पर शिवचरण माथुर को बिठाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अफवाहें गरमाने लगी हैं। प्रदेश इंका का एक गुट भविष्यवाणी कर रहा है कि वीर बहादुर के स्थान पर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जायेगा।

इस गुट की दलील है कि भले ही हरिदेव जोशी को हटाये जाने के पीछे कुछ अज्ञात कारण रहे हों, किंतु जो कारण प्रचारित किया गया है, वह है राजस्थान में सूखा राहत कार्यों में हरिदेव जोशी द्वारा ढिलाई बरतना। सूखा पूरे देश में पड़ा था और राहत कार्यों में सबसे ज्यादा घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यदि इसी कारण से हरिदेव जोशी को बदला गया है, तो निश्चित रूप से वीर बहादुर सिंह को भी हटाया जायेगा।

लेकिन पिछले २० वर्षों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की कार्यावधि का रिकार्ड तोड़ने वाले वीर बहादुर सिंह इस चर्चा को बेबुनियाद बताते हुए दावा करते हैं, "हाईकमान का मुझ पर पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी के ही कुछ स्वार्थी तत्व जब तब मेरे हटाये जाने की अफवाहें फैलाते रहते हैं।"

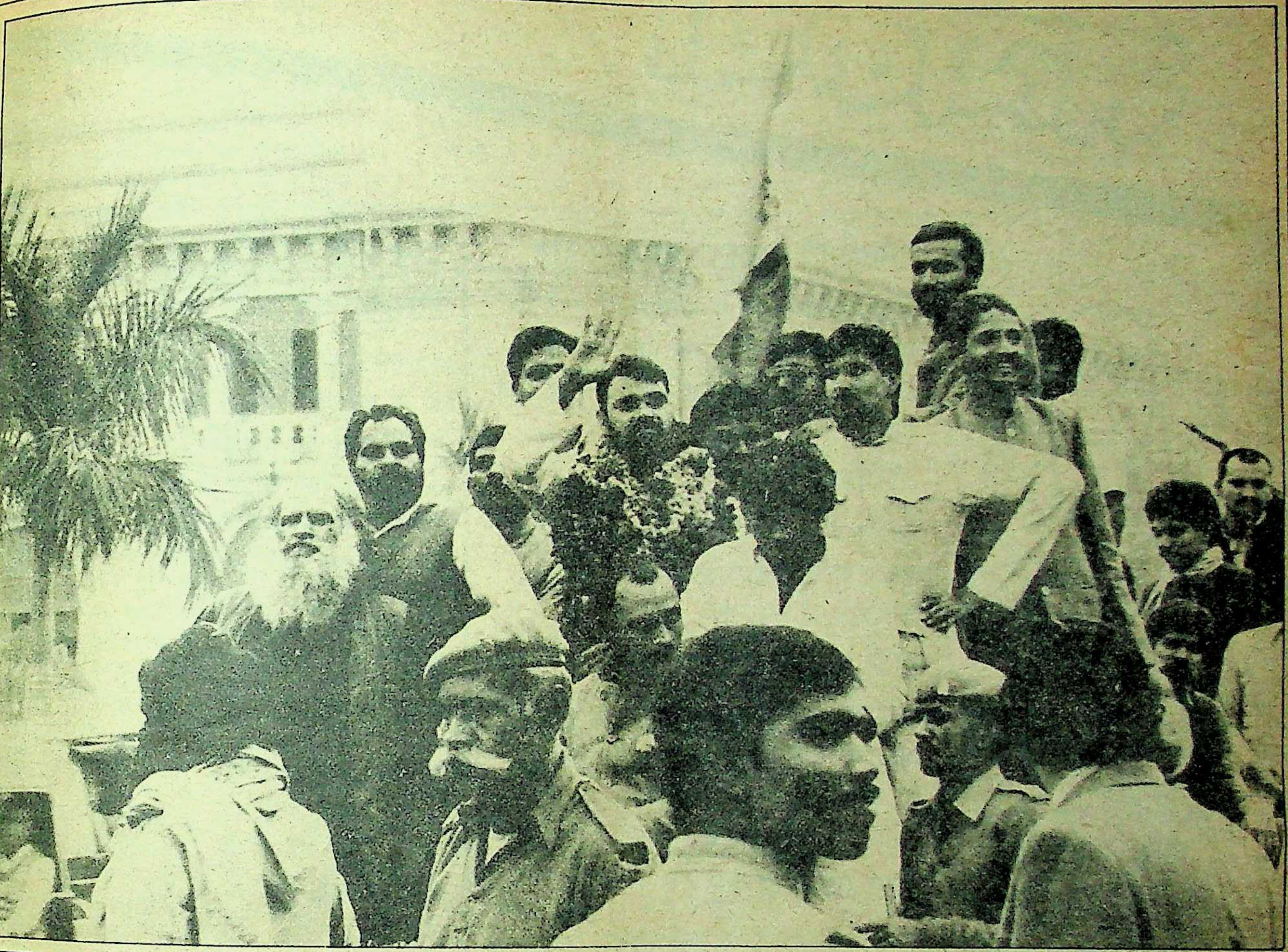

बढ़ता महत्व : भोला पाण्डेय अपने समर्थकों के बीच (माला पहने)

सत्ता-स्रोत और अपने आशंकित शत्रुओं को पहचानने में वीर बहादुर सिंह लासानी हैं। अरुण नेहरू और अमिताभ बच्चन को यथासमय उन्होंने कैसे अपना रक्षा-कवच बनाया और कैसे उतार फेंका, यह बात सभी जानते हैं। जब नारायण दत्त तिवारी से रिश्ता सुधारने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने फौरन माखनलाल फोतेदार का दामन थाम लिया। इन्हीं कलाबाजियों से वीर बहादुर सिंह ने ब्रह्मदत्त तथा के०सी० पंत जैसे धुरंधरों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बौना बना दिया। संजय सिंह का जहां उन्होंने पार्टी से ही सफाया करा दिया, वहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले अन्य लोगों—सुनील शास्त्री और अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' को पूरी तरह दबाकर रख दिया।

एकमात्र डर: वीर बहादुर, अपनी मंत्रिपरिषद के अगर किसी सदस्य से डरते हैं, तो वह हैं— लोकपति त्रिपाठी। उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश में उन्हें हमेशा मात ही मिली। चाहे इलाहाबाद मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य की सेवा-अवधि बढ़ाने का मामला रहा हो या स्वास्थ्य सचिव को बदले जाने का सवाल, हर मसले पर लोकपति त्रिपाठी की वीर बहादुर से झड़प हुई और अंततः बाजी लोकपति त्रिपाठी ने ही जीती। तमाम कोशिशों के बाद भी लोकपति त्रिपाठी का न तो वह विभाग बदलने में सफल हुए और न ही उनके पीछे कोई तेज-तर्रार राज्यमंत्री ही लगा सके। यह बात दूसरी है कि अगर लोकपति त्रिपाठी ने वीर बहादुर सिंह को कुरसी से हटाने के लिए बुंदेलखण्ड में कोई अनुष्ठान कराया, तो उसकी काट करने के लिए वीर बहादुर ने काशी (वाराणसी) में जवाबी यज्ञ करा दिया। हाल में स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने वीर बहादुर सिंह पर एक करारा वार कर दिया है। दरअसल, लोकपति के 'कार्यकलापों' पर अंकुश के लिए वीर बहादुर उनके विभागीय सचिव के पद पर अपना विश्वास पात्र अधिकारी तैनात करते रहे हैं। कुछ समय पूर्व एक स्वास्थ्य सचिव पद पर श्याम सूरी तैनात थे। स्वास्थ्य मंत्री के हर 'नेक काम' में स्वास्थ्य सचिव 'अड़ंगा' लगा देते थे। मुख्यमंत्री ने आलाकमान के कथित दबाव के बाद श्याम सूरी को हटाया, लेकिन उनकी जगह सरदार मोहिंदर सिंह को बिठा दिया, जिन्होंने श्याम सूरी की ही तरह स्वास्थ्य मंत्री के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिये। शुरू में यह परंपरा थी कि सरकारी डाक्टरों तथा स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा नियुक्ति का प्रस्ताव स्वास्थ्य निदेशालय तैयार करता था और फिर इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु स्वास्थ्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को भेजा जाता था। मंत्री और सचिव कुछ संशोधन या परिवर्तन के बाद उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन श्याम सूरी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने स्वयं प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य निदेशालय को भेजना शुरू कर दिया था। नतीजतन जहां स्वास्थ्य मंत्री का महत्व घट गया था, वहीं स्वास्थ्य निदेशालय के लोगों की 'कमाई' पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था।

मोहिंदर सिंह ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखने के साथ ही कुछ बदनाम दवा निर्माताओं को भी प्रतिबंधित कर दिया जो स्वास्थ्य निदेशालय से साठगांठ कर ऊंची कीमतों पर घटिया दवाओं की आपूर्ति करते थे। ऐसे ही कुछ दवा निर्माताओं को स्वास्थ्य मंत्री का कथित संरक्षण प्राप्त था। अपने चहेते ठेकेदारों के 'प्रतिबंधित' हो जाने से स्वास्थ्य मंत्री बौखला उठे।

मूल्य रु० ५/-
मार्च १९८८

सत्यकथा

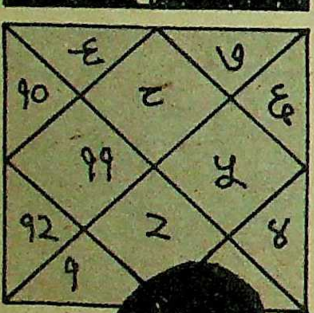

संन्यासिनी प्रेमलता का यज्ञ-रहस्य

सीतामढ़ी पहुंची एक संन्यासिनी और उसके एक ब्रह्मचारी भाई द्वारा धार्मिक आड़ में जानकी जन्मभूमि में भूमि-हड़प-यज्ञ आरंभ किए जाने की कथा

अलौकिक गणना

भूत-प्रेत बाधा दूर करने की आड़ में मेदिनीपुर के ब्राह्मण परिवारों द्वारा अपढ़ लोगों का दोहन किए जाने की कथा

बांदा का मैट्रन कांड

क्या ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक दोषी हैं ?

जिला अस्पताल की एक सहायक मैट्रन पर तोड़े गए जुल्म के पीछे अस्पताल के ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक का हाथ होने की सनसनी खेज कथा

नीता जला दी गई ?

सौराष्ट्र में एक नवविवाहिता युवती के साथ हुए हादसे के पीछे युवती की सास एवं ननद का अत्याचार होने की कथा

जसबीर की मौत का रहस्य

नंगल के एक युवक के रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो जाने में उसके ही करीबी साथियों का हाथ होने की रहस्य-कथा

तीन तिलंगों का खेल

दिल्ली के एक व्यवसायी से फिरौती प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन युवकों द्वारा उसके मासूम बच्चे के अपहरण

मंगेतर की वापसी

बचपन में हो गयी सगाई को तोड़नेवाले महबूब को महबूबा द्वारा माफ कर दिए जाने की कथा

सानू और सोलहवां वर्ष

१३ वर्ष में ही एक बच्चे की मां बन जाने वाली नेपाली युवती को सावधान संस्था द्वारा बंबई के वेश्यावृत्ति के नारकीय जीवन से मुक्त करने की मर्मस्पर्शी कथा

खजाने की खोज में बलि

राजस्थान में एक पुराने किले में खजाना मिलने के लालच में एक बालक की बलि दिये जाने की दर्दनाक कथा

साथ ही

अन्य अनेक दिलचस्प सत्यकथाएं।

गुप्तचर विक्रम के नये अभियान की सचित्र कथा

गुप्तचर विक्रम

पहली जनवरी को जब स्वास्थ्य सचिव लखनऊ से बाहर थे, तो स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने एक आदेश जारी कर दिया कि एक दिसम्बर, १९८७ या उसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने जो भी आदेश स्वास्थ्य निदेशालय को भेजे हों, उनका कार्यान्वयन तत्काल स्थगित कर दिया जाये। साथ ही उन सभी आदेशों की प्रतियां तुरंत उन्हें उपलब्ध करायी जायें।

स्वास्थ्यमंत्री के इस आदेश की प्रतियां सभी स्वास्थ्य निदेशकों से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों तक को आनन-फानन भेज दी गयीं। लोकपति त्रिपाठी के इस आदेश ने स्वास्थ्य सचिव को बिलकुल लाचार बना दिया। इस घटना से दूसरे सचिवों में भी असंतोष फैल गया। उधर स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री से कह दिया है कि ऐसी स्थिति में अब वह वर्तमान पद पर नहीं रहना चाहते हैं।

पिछले आठ वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के एकाधिकारी लोकपति त्रिपाठी ने यह 'साहसिक कदम' उठाकर जहां एक ओर वीर बहादुर सिंह को चुनौती दे दी है, वहीं राजनीतिक हलकों में भी

दीवालिया होता उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के लिए नया वर्ष आर्थिक दिवालियेपन और कंगाली से प्रारम्भ हुआ है। रिजर्व बैंक ने तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वर्ष १९८७-८८ के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत २५ अरब की योजनाओं में से अभी तक मात्र १६ अरब रुपए ही प्रदेश को मिले हैं। केन्द्र सरकार लगातार यह शिकायत कर रही है कि प्रदेश सरकार अपने संसाधन तो नहीं बढ़ा पा रही है, उलटे अंधाधुंध फिजूलखर्ची कर रही है।

प्रदेश के संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत बिक्रीकर है। वर्ष १९८७ में बिक्रीकर विभाग वसूली के निर्धारित लक्ष्य का मात्र ५७ प्रतिशत ही वसूल कर सका। इसी प्रकार अल्प बचत के मद में वर्ष १९८६ की तुलना में १९८७ में ५० प्रतिशत की गिरावट हुई है। नतीजतन अल्प बचत के मद में केन्द्र से मिलने वाली सहायता की राशि में भी कमी आ गयी है।

वर्ष १९८७ सूखे और प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष रहा है। सूखा राहत के लिए केन्द्र से मात्र डेढ अरब रुपए की सहायता प्राप्त हुई है, जबकि गुजरात और राजस्थान जैसे छोटे राज्यों को इससे चार गुनी अधिक सहायता दी जा चुकी है। सिनेमा घरों की डेढ़ महीने लम्बी हड़ताल के कारण जहां १० करोड़ रुपए के मनोरंजन कर की हानि हुई है।

प्रदेश की गरीब जनता को राहत पहुंचाने में विफल वीर बहादुर सिंह ने एक नयी परंपरा डाल दी है। मात्र डेढ़ वर्ष में वह मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ५० लाख रुपए बांट चुके हैं।

सूखे और आपदा से ग्रस्त इस प्रदेश के विधायकों के वेतन और सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि का नतीजा यह हुआ कि राज्य कर्मचारियों ने अपने वेतनवृद्धि और सुख सुविधाओं की मांग शुरू कर दी। प्रदेश में जनवरी '८६ तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग ९४ हजार पद खाली पड़े थे। इनमें चिकित्सा, नगर विकास, प्राथमिक शिक्षा, सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों तथा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के रिक्त पड़े पद शामिल नहीं थे। बजट में इन पदों के लिए १८० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन यह धन दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया। नतीजतन, अब बचत के नाम पर प्रदेश सरकार ने न केवल नयी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, वरन अस्थायी कर्मचारियों की छटनी का भी निर्णय लिया है। यानी १९८८ बेरोजगारी की संख्या बढ़ाने का साल भी होगा।

सरकारी विमानों का प्रयोग वीर बहादुर सिंह स्कूटर की तरह करते हैं। केवल डेढ़ वर्ष की अवधि में उनकी हवाई यात्राओं पर ६० लाख रुपए का ईंधन खर्च हुआ है। विधानसभा की स्वर्ण जयन्ती के नाम पर तीन करोड़ रुपए खर्च किये गये। दिल्ली में प्रदेश सरकार के दो-दो भवन होने के बावजूद एक और अतिथि गृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बम्बई में भी एक उत्तर प्रदेश आवास का निर्माण कर जन प्रतिनिधियों की मौज-मस्ती का सामान मुहैया कराया जायेगा। जाहिर है कि सरकार, बेरोजगारो के लिए रोजी उपलब्ध कराने के बजाय मंत्रियों और अफसरों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रही है।

इसी २६ जनवरी को वीर बहादुर सिंह ने लखनऊ में चार करोड़ रुपए की लागत से बननेवाले एक और अतिथिगृह की आधारशिला रख दी। इस अतिथिगृह में अतिविशिष्ट लोग ही ठहरेंगे। पूरा भवन बुलेट प्रूफ और वातानुकूलित होगा। इस गृह के निर्माण में विदेशी तकनीक का सहारा लिया जायेगा। यह अतिथिगृह तीन मंजिला होगा। इस भवन के भूतल पर प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार के लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। प्रथम तल पर राष्ट्रपति या उनके परिवार को लखनऊ आगमन के दौरान ठहराया जायेगा। द्वितीय तल पर केंद्रीय मंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के ठहरने के लिए १७ कमरे और चार सामान्य सूट होंगे। इस भवन के सभी दरवाजे इलेक्ट्रानिक विधि से खुलेंगे और बंद होंगे। इस भवन के निर्माण पर १ करोड़ ७५ लाख तथा साज-सज्जा पर सवा दो करोड़ रुपए व्यय होंगे।

समस्याओं से जूझने के बजाय उससे कतराने या फिर टालते रहने की कला में वीर बहादुर सिंह पूरी तरह माहिर हैं। जब किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली की दर बढ़ाकर ३० रुपए प्रति हार्स पावर कर दी गयी, तो महेन्द्र सिंह टिकैत के किसान आन्दोलन के आगे घुटने टेककर बढ़ी दर वापस ले ली गयी। इसी प्रकार पहले छात्रों पर विकास शुल्क लगाया गया, लेकिन जब छात्रों का आन्दोलन उग्र हुआ, तो उसे भी स्थगित करने की घोषणा की गयी। गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया गया। बाद में किसानों ने आन्दोलन की धमकी दी, तो इस अन्तर को कम कर दिया गया। राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के समय वीर बहादुर यही कहते रहे कि हम किसी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन जब आन्दोलन तीव्र होता गया, तो उन्होंने समझौता कर लिया। मुख्यमंत्री के अदूरदर्शी निर्णय और झूठे आश्वासनों के कारण उत्तर प्रदेश बरबादी की कगार पर पहुंच चुका है। गैर जिम्मेदाराना निर्णयों का खमियाजा सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है। अकेले पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के नाम पर ३०० छोटी और १०० बड़ी मोटर गाड़ियां इसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने से खरीदी गयीं। सौ कम्प्यूटर भी इसी वर्ष खरीदे गये, जो विभिन्न सचिवों और विभागों में 'शो पीस' के रूप में रखे हैं। प्रशिक्षण के अभाव में इन कम्प्यूटरों का कोई उपयोग नहीं हुआ। नतीजतन, एक करोड़ की ये मशीनें जंग खा रही हैं।

सूखा पीड़ित, खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों को रोजगार देने के लिए ३५० करोड़ रुपए खर्च कर दिये गये हैं, लेकिन कितने लोगों को किस-किस जिले में रोजगार दिया गया, कहां-कहां कितनी राशि सूखा राहत के रूप में वितरित की गयी, इसका कोई लेखा-जोखा जिला स्तर पर नहीं है। वित्त विभाग द्वारा दर्जनों बार लिखे जाने के बावजूद किसी भी जिले के जिलाधिकारी ने यह सूचना उपलब्ध नहीं करायी है।

—मोहन सिंह

तहलका मचा दिया है। उधर लोकपति त्रिपाठी के एक नजदीकी रिश्तेदार तथा देवरिया के इंका सांसद रामनगीना मिश्र ने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर के विरुद्ध खुली जंग का एलान कर दिया है। मिश्र कहते हैं, "मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को संगठित कर सरकार विरोधी आन्दोलन चला रहा हूं। वर्तमान शासन ने किसानों की दुर्दशा कर दी है। अधिकारियों ने लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा है। असली शासन तो अफसर ही कर रहे हैं। वीर बहादुर सिंह तो बस चापलूसों से घिरे रहते हैं।"

देवरिया के ही एक अन्य सांसद तथा वरिष्ठ इंकाई राजमंगल पाण्डेय भी इन दिनों वीर बहादुर से सख्त नाराज हैं। वह कहते हैं, "प्रशासन भय से चलता है। दूसरों को ईमानदारी से काम करने की सलाह देने वाले व्यक्ति का खुद का आचरण सही होना चाहिए। वीर बहादुर की कल माली हालत क्या थी और आज क्या है, यह कौन नहीं जानता? यही वजह है कि शासन वीर बहादुर का नहीं, अफसरों का चल रहा है।" पाण्डेय को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही नेतृत्व परिवर्तन होगा।

शायद यही वजह है कि इंकाइयों के एक गुट ने दिल्ली दरबार से यह मांग करनी शुरू कर दी है कि वीर बहादुर को उत्तर प्रदेश इंका का अध्यक्ष बनाया जाये।

अध्यक्ष बनाने की मांग: इस मांग पर जोर डालने के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि वीर बहादुर सिंह में संगठन को मजबूत करने की काफी क्षमता है। वर्तमान समय में महावीर प्रसाद, इंका का प्रदेश अध्यक्ष पद ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए पार्टी को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता है कि वीर बहादुर सिंह को तत्काल इंका का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाये।

इस मांग की शुरुआत लखनऊ जिला कांग्रेस-इ कमेटी ने की और इसी के बाद देखते-देखते कई जिलों से इस तरह के प्रस्ताव आने लगे। दूसरी ओर वीर बहादुर सिंह कहते हैं, "यह प्रस्ताव अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से कुछ निहित स्वार्थी तत्व ला रहे हैं।" लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदेश में पार्टी का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है।

वीर बहादुर को इंका का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग के पीछे भी लोकपति त्रिपाठी गुट का ही हाथ बताया जा रहा है। इसी २१ जनवरी को लखनऊ जिला कांग्रेस कमेटी में सांसद जगन्नाथ प्रसाद और भूतपूर्व विधायक राजा विजय कुमार त्रिपाठी ने एक प्रस्ताव पेश कर यह मांग की कि वीर बहादुर को महावीर प्रसाद के स्थान पर इंका का प्रादेशिक अध्यक्ष बना दिया जाये। प्रस्ताव रखने वाले ये दोनों ही व्यक्ति राजनीति में लोकपति के नजदीक समझे जाते हैं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रस्ताव पर इन दोनों नेताओं के अलावा इंका के जिलाध्यक्ष अब्दुल हकीम ने भी हस्ताक्षर किये। २३ जनवरी को जब इस प्रस्ताव की जानकारी वीर बहादुर सिंह को मिली, तो उन्होंने सांसद जगन्नाथ प्रसाद और राजा विजय कुमार त्रिपाठी को अपनी कोठी पर 'तलब' किया और उनसे यह लिखा लिया कि 'हम दोनों' इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

वीर बहादुर का हर वार खाली: लोकपति त्रिपाठी

उधर इंका के जिलाध्यक्ष अब्दुल हकीम का कहना है, "प्रस्ताव उन्हीं दोनों लोगों ने रखा था और प्रस्ताव पर दस्तखत किये थे। अब बयान बदलते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस में तो यह सब चलता ही रहता है। इसी बहाने मुख्यमंत्री से कुछ 'काम' करा लिये होंगे।"

अब्दुल हकीम को शीला कौल की कृपा प्राप्त है। वह खुलकर आरोप लगाते हैं, "पूरे प्रदेश में सूखा राहत के नाम पर अफसरों ने लूट-खसोट की है। कहीं कोई काम नहीं हुआ है। बीस सूत्री कार्यक्रम में वैसे तो प्रदेश प्रथम आया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे आंकड़े फर्जी हैं।"

लोकपति त्रिपाठी को प्रदेश की राजनीति में बौना बनाने के लिए वीर बहादुर ने उनके प्रबल समर्थकों को तोड़ना शुरू कर दिया। विधायकों में लोकपति के कट्टर समर्थक डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल अब पूरी तरह वीर बहादुर के साथ आ गये हैं। पिछले दिनों आगरा के दौरे में वीर बहादुर ने अपने पुराने चहेतों—आजाद कुमार कर्दम और ओमप्रकाश जिंदल—की पूरी तरह उपेक्षा कर सारे कार्यक्रमों में डाक्टर कौशल को साथ रखा। कर्दम और जिंदल को मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से पहले बढ़ावा दिया था, उसी का परिणाम है कि १९७७ से पूर्व साधारण हैसियत वाले इन दोनों लोगों की गिनती आज आगरा के संपन्न लोगों में हो रही है। कर्दम और जिंदल की उपेक्षा कर डाक्टर कौशल को अपने साथ मिला लेने का परिणाम यह हुआ कि अब डाक्टर कौशल खुले आम यह कहने लगे हैं, "अगला विधानसभा का चुनाव अगर वीर बहादुर के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ, तो निश्चित रूप से इंका को बहुमत मिलेगा।"

इस सवा दो वर्ष के कार्यकाल में श्री सिंह ने अपने विरोधियों को हर प्रकार से दबाये रखने की भरपूर कोशिश की है। विपक्षी दलों के जहां सभी प्रमुख नेताओं को उन्होंने 'पटाकर' रखा, वहीं अपने खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्र के मालिकों और पत्रकारों को भी मिलाकर चलने में वह पूरी तरह सफल रहे हैं। इस सबके बावजूद विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम उनकी ही पार्टी का एक गुट लगातार कर रहा है। इस गुट को लोकपति त्रिपाठी का खुला संरक्षण प्राप्त है। हाल में इस गुट में सहकारिता मंत्री अरुण कुमार सिंह भी शामिल हो गये हैं।

आलाकमान की नाराजी: यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार में सोनिया गांधी का बरदहस्त प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद यह बात जोर-शोर से फैलायी जा रही है कि राजीव गांधी अब उनसे नाराज हो गये हैं। इस बारे में विरोधी गुट के लोग तीन प्रमुख उदाहरण देते हैं:

पहला तो यह कि वीर बहादुर के कड़े विरोध के बावजूद राजीव गांधी ने भोला पाण्डेय को युवक कांग्रेस का अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त कर दिया है। वीर बहादुर के समर्थक भी भोला पाण्डेय की इस नयी नियुक्ति को वीर बहादुर की पहली मात मान रहे हैं। भोला पाण्डेय, वीर बहादुर के राजनीतिक दुश्मन तथा गोरखपुर के निर्दलीय विधायक हरिशंकर तिवारी के खास आदमी माने जाते हैं। जिन दिनों वीर बहादुर सिंचाई मंत्री थे, तब तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने वीर बहादुर सिंह की हत्या किये जाने की निश्चित साजिश का सूत्र पुलिस के हाथ लगने का दावा किया था। उस समय यह भी रहस्योद्घाटन हुआ था कि पुलिस का ही एक इंसपेक्टर, एक माफिया गुट के इशारे पर वीर बहादुर की हत्या करना चाहता था। इस इंसपेक्टर के विरुद्ध जब कार्रवाई की गयी, तो लोकपति त्रिपाठी ने उस इंसपेक्टर को संरक्षण दिया और भोला पाण्डेय ने पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में जाकर उन्हें काफी भला-बुरा भी कहा था। युवक कांग्रेस के महामंत्री मनोनीत होने पर लखनऊ में हुए भोला पाण्डेय के भव्य स्वागत को देखकर तमाम लोग यह कहते सुने गये कि अब राजीव गांधी ने वीर बहादुर के गले में नकेल डाल दी है।

दूसरा मामला हरिद्वार में आयोजित सेवादल के शिविर का है। वीर बहादुर नहीं चाहते थे कि १५ जनवरी को राजीव गांधी सेवादल के शिविर में शामिल होने हरिद्वार जायें, लेकिन प्रधानमंत्री हरिद्वार पहुंच गये। वहां एक रोचक घटना घट गयी। जिस समय मुख्यमंत्री सेवादल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, गजीव गांधी ने अपने बगल में खाली पड़ी कुरसी पर सेवादल के प्रादेशिक अध्यक्ष जगदंबिका पाल को बुलाकर बिठा लिया और उनसे गुप-चुप बातें करने लगे। वीर बहादुर ने जल्दी-जल्दी भाषण समाप्त किया और अपनी कुरसी के पास आ गये। जगदंबिका पाल ने

उठने का उपक्रम किया, तो प्रधानमत्री ने फिर बिठा लिया। करीब चार मिनट तक वीर बहादुर खड़े रहे और इस बीच उनकी जगदंबिका पाल से 'कानाफूसी' होती रही। अपने विरोधी को बख्शी गयी इस अहमियत से मुख्यमंत्री का दहल जाना स्वाभाविक है।

तीसरी घटना गोरखपुर की है। १५-१६ जनवरी, १९८८ को प्रधानमंत्री गोरखपुर गये थे। वहां उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। नियमानुसार किसी जिले में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनानें की सीधी जिम्मेदारी वहां के जिलाधिकारी की होती है। लेकिन वीर बहादुर सिंह ने यह जिम्मेदारी गोरखपुर नगर महापालिका के प्रशासक डी०के० कोटिया को सौंप दी थी। कोटिया को वीर बहादुर का विश्वासपात्र बताया जाता है। बताया जाता है कि गोरखपुर के गोलघर इलाके में स्थित वीर बहादुर की किराये वाली बहुचर्चित कोठी को मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम खरीदवाने में कोटिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

प्रधानमंत्री के दौरे की जिम्मेदारी कोटिया पर डालने की शिकायत वीर बहादुर के विरोधी गुट ने गोरखपुर में ही राजीव गांधी से की। वीर बहादुर ने वहां इस बात की काफी कोशिश की कि प्रधानमंत्री उनके विरोधी गुट के लोगों से न मिलें, लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी ने उनसे खुलकर बातें कीं। इस दौरान प्रियरंजन दासमुंशी लगातार प्रधानमंत्री के साथ रहे। दासमुंशी वीर बहादुर-विरोधी समझे जाते हैं।

भ्रष्टाचार : इन तीनों घटनाओं ने मुख्यमंत्री-विरोधी अभियान को गति दी है। फलतः विरोधी गुट के लोगों ने कुछ विपक्षी नेताओं से साठगांठ कर वीर बहादुर के भ्रष्टाचारों को उजागर करना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत यह आरोप लगाया जाने लगा है कि मुख्यमंत्री देहरादून की एक आलीशान कालोनी में अमरदेव सिंह के फर्जी नाम से लाखों रुपए की लागत का भव्य महल बनवा रहे हैं। बंबई में जयप्रकाश एसोसिएट्स के साथ मिलकर एक शानदार होटल का निर्माण करा रहे हैं।

देहरादून में कथित महल के निर्माण के आरोप का वीर बहादुर ने कोई खंडन नहीं किया है, जबकि बंबई के होटल के बारे में उनका कहना है, "यह बिलकुल गलत प्रचार किया जा रहा है। मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।"

लेकिन इस 'मनगढ़ंत आरोप' के जवाब में उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी मोर्चे के संयोजक तथा लोकदल-ब के नेता, मुलायम सिंह यादव कहते हैं, "मुख्यमंत्री बनने के बाद वीर बहादुर सिंह ने कमीशन और घूस के रूप में करोड़ों रुपए कमाये हैं। वह हद से ज्यादा जोड़-तोड़ में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि वह विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाने देना चाहते हैं, जिसमें वह या उनके परिवार का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हो। सूखे से निपटने के लिए केंद्र से मिले ४३ करोड़ रुपयों का कोई हिसाब-किताब नहीं है।"

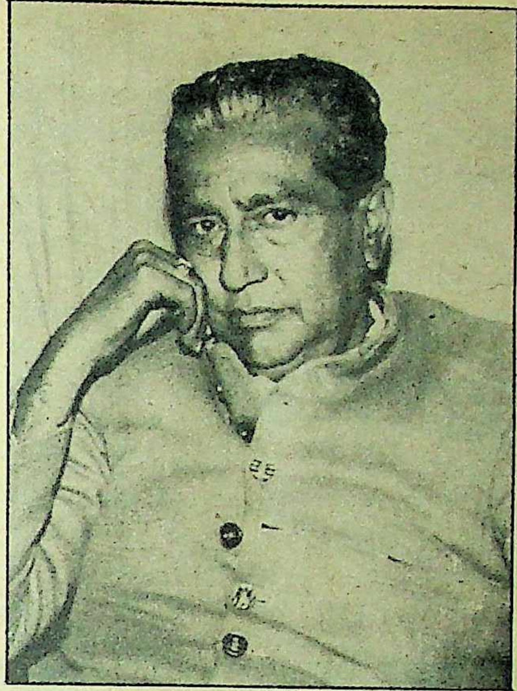

बीस सूत्री आंकड़े फर्जी हैं: अब्दुल हकीम

दरअसल, मुख्यमंत्री-पद का दायित्व संभालते ही वीर बहादुर ने स्वच्छ प्रशासन की दिशा में जो तेजी दिखायी थी, वह तीन महीने में ही फिस्स बोल गयी थी। उन्होंने उस समय बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि अब गुण्डे ठेके नहीं ले सकेंगे, सफेदपोशों के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलायी जायेगी। चूंकि वीर बहादुर के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व गोरखपुर, फैजाबाद, हरिद्वार और रायबरेली आदि जिलों में ठेकों के लिए माफिया गिरोहों के बीच गोलियां चलने की घटनाएं हो चुकी थीं। इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जब गिरोहबंद कानून लागू कर ऐसे तत्वों के विरुद्ध जेहाद शुरू किया गया, तो आम लोगों ने राहत की सांस ली। ठीक ढंग से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को संतोष हुआ। कुछ प्रशासनिक फेरबदल से ऐसे अधिकारियों में भय उत्पन्न हुआ, जो माफिया गिरोहों को संरक्षण देते थे, लेकिन ६ महीने बाद ही सब कुछ फिर पहले जैसा होने लगा।

यही नहीं माफिया गिरोहों का प्रभाव लखनऊ तक में पहुंच गया। २८ दिसंबर, १९८७ को क्रांतिकारी मोर्चे द्वारा उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान लखनऊ में इसलिए सफल रहा कि एक माफिया सरगना ने खुले आम यह चेतावनी दी थी कि जिस व्यापारी ने दुकान खोली, उसकी दुकान लूट ली जायेगी। इस तरह की चेतावनी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। लखनऊ में उस दिन एक भी दुकान नहीं खुली। यही नहीं राजू भटनागर को संरक्षण देनेवाले लोगों के नाम प्रकाश में आने के बावजूद किसी का अभी तक बाल बांका नहीं हुआ है। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सुभाष जोशी को इसलिए जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्थानीय माफिया की नाक में नकेल डालना शुरू कर दिया था।

वीर बहादुर सिंह इन दिनों लोकायुक्त के मामले को लेकर भी विवादों के घेरे में आ गये हैं। कहा जा रहा है कि लोकायुक्त मुर्तजा हुसैन का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके कारण पन्ना सेठ सहित कई अधिकारी फंस रहे थे। इसी 'उपकार' की बदौलत कानून में संशोधन करके उनका कार्यकाल बढ़ा है, जबकि उन्हें ३१ दिसंबर को सेवामुक्त होना था।

इससे भी मजेदार बात तो यह है कि इन्हीं लोकायुक्त ने १९८२ में सरकार से आग्रह किया था कि लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त की जांच की परिधि में ले लिया जाये। लेकिन उस समय संशोधन नावाजिब करार दिया गया था।

इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का है। एक समय में इसके अध्यक्ष संजय सिंह थे। उनके पद से हटते ही वीर बहादुर सिंह ने दुग्ध संघ में हुए भ्रष्टाचार की जांच गुप्तचर विभाग से करायी। जांच के दौरान लाखों रुपए के घोटाले का पता चला। मामले की पुलिस में रिपोर्ट हुई, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री पर कौन-सा दबाव पड़ा कि दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करना तो दूर, निलंबित तक नहीं किया गया। दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर वीर बहादुर ने अपने एक खास व्यक्ति शिवनाथ सिंह कुशवाहा को बिठा दिया। अब वही कथित भ्रष्ट अधिकारी, कुशवाहा के 'भक्त' हो गये हैं।

अपने विरोधी गुट की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वीर बहादुर ने मंत्रिमंडल विस्तार का दाना एक बार फिर फेंक दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं, "मैं यह साफ-साफ कह रहा हूं कि अगले तीन महीनों (अप्रैल १९८८) में मैं अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार जरूर कर दूंगा।"

इस घोषणा के बाद वीर बहादुर को यह उम्मीद हो गयी है कि पार्टी के जो थोड़े-बहुत विधायक उनका विरोध कर रहे हैं, वे अब उनके साथ हो जायेंगे। लेकिन इंका के एक वरिष्ठ विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री कहते हैं, "इस समय वीर बहादुर की मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं लोगों के पास हैं जो पूरी तरह अक्षम हैं या मुख्यमंत्री के यहां 'दरबारगिरी' करते हैं। चाहे रामनाथ मुंशी हों या शिवबालक पासी, चेतराम गंगवार हों या सरस्वती अम्माल। भला ऐसे लोगों के बीच मंत्री-पद मिलने के बाद हम कहां 'फिट' हो सकेंगे।"

लेकिन आलाकमान को उत्तर प्रदेश में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वी०पी० सिंह की आंधी को रोक सके और चुनाव जिताने की 'खासियत' रखता हो—और यह 'गुण' वीर बहादुर में है। जाहिर है उनके कुरसी पर बने रहने का यही सबसे बड़ा कारण है।

—[illegible]जय कुमार

छाया: [illegible]मोहन शर्मा

वीर बहादुर ने ब्रह्मदत्त को बौना बना दिया

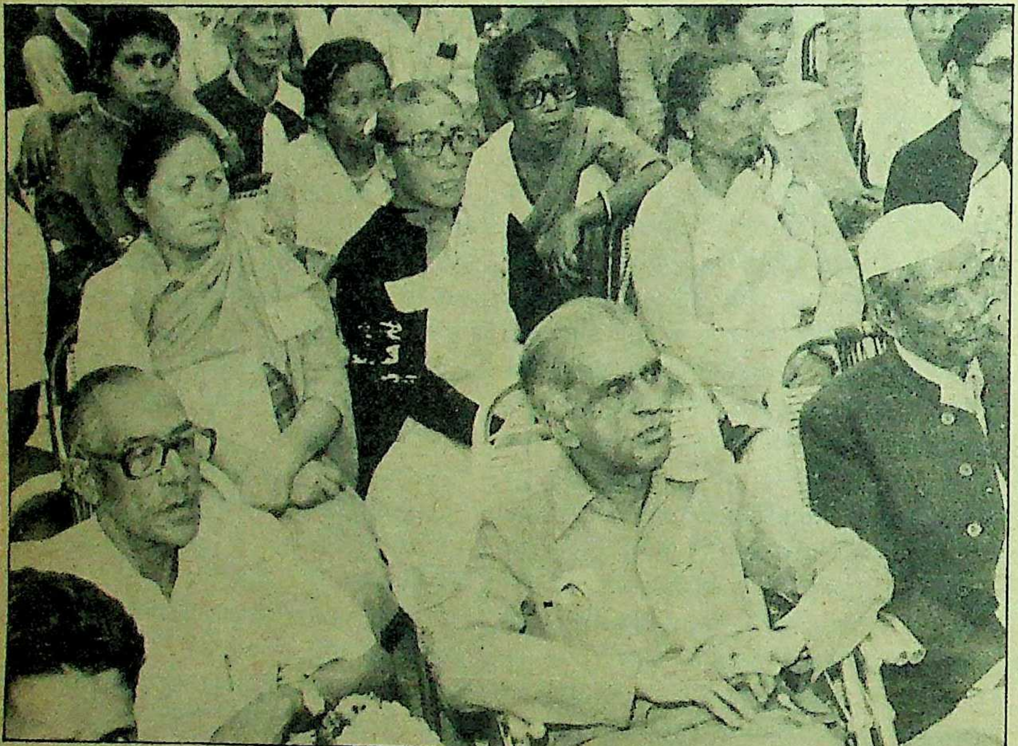

मंच से नीचे: 'चौपाल' में जनता के बीच ब्रह्मदत्त

इन दिनों मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने पेट्रोलियम राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त को अपना निशाना बना रखा है। बहाना तो उनके सुपुत्र नवप्रभात शर्मा के गैर-राजनीतिक संगठन 'चौपाल' को बनाया जा रहा है, मगर मकसद गढ़वाल की राजनीति से ब्रह्मदत्त को अलग-थलग करना और उन्हें अपने जिले देहरादून की गुटबाज इंकाई राजनीति में उलझाये रखना है। इस तरह मुख्यमंत्री की इस रणनीति के पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह कि इंका आलाकमान की निगाह में भावी मुख्यमंत्री पद के लिए ब्रह्मदत्त का कद बौना बना देना और दूसरा, उनके खैरख्वाह केन्द्रीय वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी को उनकी औकात दिखाना।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में जब भी मुख्यमंत्री बदलने की बात चलती है, तो दो तीन नाम सामने आ जाते हैं। इस समय ब्रह्मदत्त का नाम जोरों पर है और ऐसा समझा जाता है कि उन्हें नारायणदत्त तिवारी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री वीर बहादुर येन-केन प्रकारेण ब्रह्मदत्त को छोटा साबित करने पर तुले हुए हैं।

वीर बहादुर की हार: देहरादून इस समय इंका राजनीति में जारी इस युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ चौपाल और उसके संयोजक सुरेन्द्र अग्रवाल हैं, तो दूसरी तरफ चकराता के विधायक गुलाबसिंह (जिला इंकाध्यक्ष देहरादून) और शहर के विधायक हीरासिंह विष्ट (शहर इंकाध्यक्ष) हैं। ये दोनों 'सिंह' वीर बहादुर के इशारे पर पैंतरेबाजी कर रहे हैं। दरअसल, गैर-राजनीतिक मंच के रूप में चौपाल का अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी में ब्लाक स्तर तक गठन करवाकर ब्रह्मदत्त ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर गढ़वाल की इंका राजनीति से उन्हें अलग-थलग करने की चेष्टा जारी रही, तो वह संगठनात्मक तरीके से इसका माकूल जवाब देने की स्थिति में हैं। उनकी इस रणनीति को युवा इंका नेता सुरेन्द्र अग्रवाल और टिहरी 'चौपाल' के संयोजक भूदेवलखेड़ा ने अंजाम दिया है। ये दोनों ब्रह्मदत्त के खास आदमी समझे जाते हैं। नवप्रभात इन दोनों के सहायक के रूप में शुरू के दिनों में चौपाल की बैठकों में उपस्थित रहकर काम करने का अनुभव हासिल करते रहे हैं।

ब्रह्मदत्त और वीर बहादुर के बीच सार्वजनिक रूप से पहली जोर-आजमाइश १५ नवम्बर '८७ को हुई। एक तरफ देहरादून नगरपालिका के मैदान में आलीशान शामियाने में चौपाल की सभा चल रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भवन में आनन-फानन में बुलायी गयी इंका कार्यकर्ताओं की बैठक। चौपाल में ब्रह्मदत्त विराजमान थे, तो कांग्रेस भवन में वीर बहादुर। मात मुख्यमंत्री की हुई। चौपाल में टिहरी के ग्रामीण-अंचलों से आये लगभग पांच हजार लोग थे, जिनमें कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी सभी तरह के लोग शामिल थे, जबकि कांग्रेस भवन में सिर्फ डेढ़ सौ कार्यकर्ता। चौपाल में विधायक गुलाबसिंह के गृह स्थान जौनसार बावर के भी सैकडों लोग हिस्सा ले रहे थे। इंका कार्यकर्ताओं की बैठक निर्धारित समय से तीन घंटे बाद हुई और तब तक चौपाल खतम हो चुकी थी।

चौपाल के पहले वार्षिक जिला सम्मेलन के अवसर पर बीस सूत्री कार्यक्रम की मंडलीय समीक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति को देहरादून के कांग्रेसी हलकों में कई तरह से लिया गया है। कुछ इंकाइयों का कहना है, "इस बैठक के बारे में तीन दिन पहले तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। यहां तक कि हमें यह भी भान नहीं था कि बैठक में मुख्यमंत्री तशरीफ लायेंगे।" चौपाल के उत्साही कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करने की आड़ में मुख्यमंत्री का उद्देश्य सरकारी अफसरों को चौपाल में जाने से रोकना था। कुछ लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री वीर बहादुर खुद चौपाल की राजनीति का जायजा लेने आये थे, ताकि वह ब्रह्मदत्त के खिलाफ आलाकमान को सचेत कर सकें। वैसे ब्रह्मदत्त ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। शिकायत से पहले ही उन्होंने आलाकमान के पास चौपाल के कैसेट भिजवा दिये थे। पता चला है कि प्रधानमंत्री ने चौपाल के आयोजन की सराहना भी की है। जो भी हो, इंका के अन्दर और इंका के बाहर देहरादून के तटस्थ लोग १५ नवम्बर की तारीख को ब्रह्मदत्त और वीर बहादुर के बीच सार्वजनिक जोर-आजमाइश मानते हैं और इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इस शक्ति परीक्षण में वीर बहादुर बुरी तरह मात खा गये।

यह दीगर कहानी है कि १५ नवम्बर के अपमान का बदला वीर बहादुर ने २८ नवम्बर को हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों को जोड़ने के लिए बनाये गये 'मिनस पुल' के उद्घाटन के अवसर पर ब्रह्मदत्त को नजरंदाज करके लिया। इस पुल का उद्घाटन पहले १८ नवम्बर को होना था। अधिकारियों ने इसके लिए ब्रह्मदत्त को राजी कर लिया था। शिलापट भी बन गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह भी आमंत्रित किये गये थे। अचानक उद्घाटन तिथि बदलकर २८ नवम्बर कर दी गयी। लखनऊ से कुछ ऊंची राजनीति चली। उद्घाटनकर्ता बदल गये। ब्रह्मदत्त की जगह मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह हो गये। दलील यह दी गयी कि मामला दो राज्यों का है। जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश का माकूल प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। इस सारी बात के पीछे मुख्य भूमिका पर्वतीय राज्यमंत्री रामऔतार दीक्षित की रही। बहरसूरत, क्षेत्रीय सांसद होने के नाते केन्द्रीय राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त भी उद्घाटन अवसर पर आये, मगर उन्हें समारोह में नजरंदाज किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उद्घाटन के अवसर पर हुए यज्ञ में आहुति देने के लिए ब्रह्मदत्त को विधायक गुलाबसिह का सहारा लेना पड़ा। इस सिलसिले में जब 'माया' ने सचाई जाननी चाही, तो ब्रह्मदत्त ने कहा, "यह बात सरासर गलत है। यज्ञ करने वाले पंडित को दक्षिणा तो मैंने ही दी। उस समय किसी के जेब में पैसे नहीं थे। आहुति न डालता, तो दक्षिणा क्यों देता?"

पुराने मतभेद : ब्रह्मदत्त को बौना बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री का साथ देने वाले विधायक गुलाबसिह और विधायक हीरासिह विष्ट की उनसे अन्दर-ही-अन्दर राजनीतिक अनबन है। इसका फायदा वीर बहादुर सिह उठा रहे हैं। हीरासिह इसलिए नाराज हैं कि १९८५ में विधानसभा के लिए टिकट मांगते समय ब्रह्मदत्त ने उनका न केवल साथ दिया, बल्कि अपने ही एक समर्थक युवा इंकाई विनोद चंदोला को टिकट दिलवाने की पैरवी की। वह इसमें सफल भी रहे। यह दूसरी बात है कि गढ़वाल की राजनीति में ब्राह्मण-ठाकुर जाति समीकरण की वजह से चंदोला का टिकट घोषणा के बाद भी कट गया। इस काम में गढ़वाल के सांसद चन्द्रमोहन सिंह नेगी (अब जनमोर्चा में) ने विश्वनाथ प्रताप सिंह (तब टिकट बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे) के माध्यम से निर्णायक रोल अदा किया। यही नहीं चकराता से गुलाबसिह के मुकाबले पंडित शिवराम का नाम ब्रह्मदत्त ने उम्मीदवार के रूप में चलाया। यह बात दीगर है कि ब्रह्मदत्त-नारायणदत्त लाबी इसमें सफल नहीं हुई। वैसे भी गुलाबसिह की ब्रह्मदत्त से पुश्तैनी लाग-डांट है।

गुलाबसिह की वीर बहादुर से राजनीतिक दोस्ती लगभग उतनी ही पुरानी है, जितनी कि उनकी ब्रह्मदत्त से रंजिश। १९८० में प्रदेश में चौधरी चरण सिह के नेतृत्व में कांग्रेस और भारतीय क्रान्तिदल की मिली-जुली सरकार थी। तब वीर बहादुर और गुलाबसिह दोनों ही पहली बार उपमंत्री के रूप में सरकार में शामिल किये गये थे। तब से कुछ ठाकुरवाद के नाम पर और कुछ व्यक्तिगत पसंद के आधार पर दोनों की दोस्ती परवान चढती गयी। वीर बहादुर सिह ने दो-एक बार गुलाबसिह को अपने मंत्रिपरिषद में लेने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए।

चौपाल गैरराजनीतिक? : जो भी हो, चौपाल की राजनीति टिहरी संसदीय क्षेत्र के पांचों विधानसभाई इलाकों—उत्तर काशी, देवप्रयाग, टिहरी, मसूरी और चकराता—के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना रंग जमा रही है। देवप्रयाग के विधायक शूरवीर सिंह सजवाण और चकराता के विधायक गुलाबसिह को छोड़कर अन्य तीन इंका विधायकों को चौपाल से कोई विशेष शिकायत नहीं है। वे इसे गैर राजनीतिक मंच मानते हैं। देहरादून के स्नातक क्षेत्र के इंकाई विधान परिषद सदस्य नित्यानंद स्वामी को चौपाल से कोई गुरेज नहीं है। अलबत्ता शहर के विधायक हीरासिह का कहना है, "कुछ लोगों ने कांग्रेस से निकलकर जनमोर्चा जैसे संगठन का गठन किया है, तो कुछ लोग कांग्रेस में रहकर उसी प्रकार की दूसरी संस्थाएं बना रहे हैं।" हालांकि उन्होंने खुलकर चौपाल को नहीं कोसा है, फिर भी वह इसे इंका के लिए जनमोर्चा से खतरनाक संगठन मानते हैं।

देवप्रयाग के इंका विधायक शूरवीर सिह सजवाण का मानना है कि चौपाल गैर राजनीतिक संगठन नहीं है और इसका गठन टिहरी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किया गया है। सजवाण का कहना है, "इस संगठन के पीछे उन इंकाई नेताओं का हाथ है जिनकी छवि समाज में खराब हो चुकी है।" इसी तरह विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित भीष्म देव नौटियाल, युवा जनता के देहरादून नगर अध्यक्ष अजय शर्मा और लोकदल के जिला महामंत्री शंकरचंद रमोला, चौपाल को विशुद्ध राजनीतिक संगठन मानते हैं और इन लोगों का कहना है, "गैर राजनीतिक मंच के रूप में चल रहे चौपाल के पीछे राजनीतिक खेल जारी है।" अजय शर्मा का मानना है, "चौपाल ब्रह्मदत्त के पुत्र नवप्रभात शर्मा को राजनीति में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।" इसके विपरीत नवप्रभात और सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है, "हमारा मंच चौपाल पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है। गांवों में रहने वाले लोग इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि अपनी बात कहने के लिए रोज जिला मुख्यालय या देश-प्रदेश की राजधानियों तक जा सकें। चौपाल इन्हीं लोगों की विकास संबंधी शिकायतों और इनके विचारों को इकट्ठा कर उचित स्थान तक पहुंचाने का माध्यम है। हमारे दो अनुशासन वाक्य हैं—पहला, यह संगठन गैर-राजनीतिक रहेगा, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिल-बैठकर सद्भावना के वातावरण में विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी की निंदा या प्रशंसा नहीं करते।" टिहरी के चौपाल के संयोजक भूदेव लखेड़ा का विचार है, "हम ठोस रचनात्मक काम कर रहे हैं। आलोचना करनेवाले सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। हमें इन आलोचनाओं पर कोई एतराज नहीं।"

चौपाल और अन्य कार्यक्रमों के जरिये ब्रह्मदत्त और वीर बहादुर के बीच जो खींचतान चल रही है, उसका मैदान गढ़वाल मण्डल बना हुआ है। जहां ब्रह्मदत्त इस क्षेत्र में जमने के लिए कृत संकल्प हैं, वहीं वीर बहादुर उन्हें उलझाये रखने के लिए अपने हथकंडे चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वह देहरादून की ४७ बार यात्रा कर चुके हैं। देखना है, वीर बहादुर और ब्रह्मदत्त में किसकी जीत होती है।

खुद ब्रह्मदत्त का मानना है, "चौपाल से मुझे बल मिला है। मैं हर गांव तक चाहकर भी नहीं पहुंच पाता। सरकार योजना बनाकर क्षेत्र में काम करवा सकती है। क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं, इसकी जानकारी तो वहां की जनता ही दे सकती है। चौपाल इसका माध्यम है। मेरी तो इच्छा यह है कि हर सांसद और विधायक अपने-अपने इलाके में चौपाल बुलवाये, ताकि जनता की तकलीफों को जानने में उसे मदद मिल सके। सरकारी अमले के बूते यह काम नहीं छोड़ा जा सकता।" चौपाल के माध्यम से नवप्रभात को राजनीति में उतारने की भूमिका पर किये गये सवाल के उत्तर में वह कहते हैं, "मैं कौन होता हूं उसे राजनीति में उतरने से रोकने वाला। चाहने पर भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। मगर इसके लिए एक शर्त है, पहले वह बैंक की नौकरी छोड़े और जनता में जाकर नीचे से काम करना सीखे। मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर राजनीति में नहीं उतरा। मैं चाहूंगा कि वह भी मेरे कंधे पर बैठकर राजनीति में न उतरे।"

बहरसूरत, 'बाहरी' समझे जानेवाले ब्रह्मदत्त चौपाल के माध्यम से पहाड़ की आम जनता तक पहुंच रहे हैं और अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। फिर भी, चौपाल और अन्य कार्यक्रमों के जरिये ब्रह्मदत्त और वीर बहादुर के बीच जो खींचतान चल रही है, उसका मैदान गढ़वाल मण्डल बना हुआ है। जहां ब्रह्मदत्त इस क्षेत्र में जमने के लिए कृत संकल्प हैं, वहीं वीर बहादुर उन्हें उलझाये रखने के लिए अपने हथकंडे चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वह देहरादून की ४७ बार यात्रा कर चुके हैं। देखना है, वीर बहादुर और ब्रह्मदत्त में किसकी जीत होती है।

—अशोक रजनीकर और सुरेश द्विवेदी

छाया: बी०एन०पाण्डेय

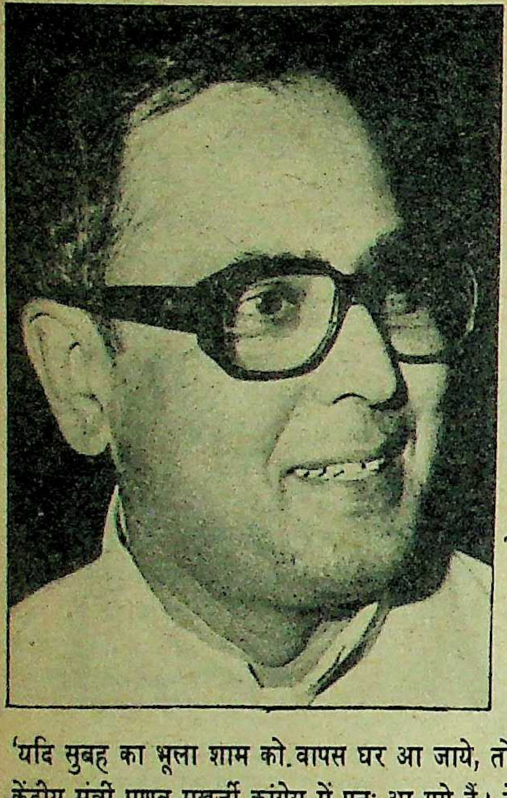

लौट के प्रणब घर को आये

'यदि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाये, तो उसे भूला नहीं कहते' इसी तर्ज पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में पुनः आ गये हैं। लेकिन क्या कांग्रेस उनको सचमुच अपना लेगी और उनकी पूर्ववत स्थिति कांग्रेस-इ में बरकरार हो पायेगी ?

६ दिसम्बर की शाम बेटी के विवाह का अवसर वैसे भी मंगलमय और प्रसन्नतादायक था, किंतु भूतपूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के हर्षोल्लास के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था—उसमें सम्मिलित होने वाले कांग्रेसियों की संख्या और उनकी वरिष्ठता। उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, नारायण दत्त तिवारी आदि की उपस्थिति किसी के लिए भी गौरव की बात होती। किंतु दिल्ली के राजनीतिक दांव-पेचों को भलीभांति जानने-समझने वाले प्रणब मुखर्जी के लिए कांग्रेस में अपनी वापसी का इससे बेहतर संकेत नहीं हो सकता था।

अंततः हुआ भी यही। यद्यपि औपचारिक रूप से ६ वर्ष के लिए निष्कासित प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस में वापस नहीं लिया गया है, किंतु त्रिपुरा-मेघालय में विधानसभा के चुनावों के अभियान के लिए प्रणब मुखर्जी और उनके सहयोगी अशोक भट्टाचार्य को निमंत्रण देकर आलाकमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने विद्रोही सदस्य के प्रति उसकी नाराजगी लगभग दूर हो चुकी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस और केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री संतोष मोहन देव ने टेलीफोन पर निमंत्रण देकर मतभेद मिटाने में पहल की। जवाब में पूर्व वित्तमंत्री ने केवल इसे शिरोधार्य किया, किंतु अपनी आधी-अधूरी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को भंग कर देने की घोषणा भी की।

उल्लेखनीय है कि हाल में बदले आलाकमान के रवैये के कारण कई विद्रोही कांग्रेसियों को पुनः प्रवेश पाने की अफवाह जोर पकड़ रही थी। इनमें प्रमुख नाम थे मध्य प्रदेश के श्यामाचरण शुक्ल (विशेषकर भाई विद्या चरण को अप्रभावी बनाने की नीयत से), महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान अंतुले (कदाचित चह्वाण, वसंत दादा पाटिल और शरद पवार के असंतोष को संतुलित करने के लिए), उड़ीसा की नंदिनी सत्यपथी (संभवतः अपयश के शिखर पर आरूढ़ मुख्यमंत्री जे०बी० पटनायक के विकल्प के लिए)। प्रणब मुखर्जी का नाम तो यदा-कदा ही लिया जाता था। अतः अन्य सभी को पीछे छोड़ उनकी वापसी यदि पूर्णतया अप्रत्याशित नहीं, तो चकित करने वाली अवश्य है।

स्वप्न : इस ताबड़तोड़ निर्णय का तात्कालिक कारण त्रिपुरा के चुनाव हैं। नागालैंड में विजय प्राप्त करने और आक्रामक मुद्रा अपनाने के पश्चात कांग्रेस वामपंथियों के पूर्वोत्तर गढ़ में सेंध लगाने का स्वप्न देख रही है। प्रणब मुखर्जी इस क्षेत्र का सारा कच्चाचिट्ठा जानते हैं। उनका इस मुहिम में जुड़ना लाभदायक हो सकता है, ऐसा कांग्रेसी खेमे को विश्वास है। ज्ञात रहे कि १९८३ में कांग्रेसी गठजोड़ वामपंथी दलों से ८ प्रतिशत वोट से पराजित हुआ था। अतः इस बार वह जी-जान से चुनाव मैदान में उतर पड़ी हैं। विजयश्री हासिल करने में 'विद्रोही' प्रणब मुखर्जी को वापस बुलाने में भी उसने कोई देर व संकोच करना उचित नहीं समझा है।

वैसे भी चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित या रूठे हुए लोगों को मनाने और उसका उपयोग करने की परंपरा-सी बना ली है। १९८५ में सिद्धार्थशंकर राय को कलकत्ता महापालिका के चुनाव-प्रचार के लिए बुलाया गया था। पिछले वर्ष मार्च में विधानसभा के लिए वयोवृद्ध नेता पी०सी० सेन की सेवाएं प्राप्त की गयी थीं।

त्रिपुरा चुनाव के अतिरिक्त प्रणब मुखर्जी के पुनर्प्रवेश का एक अन्य और महत्वपूर्ण कारण पश्चिम बंगाल में वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व का दीवालियापन है। तमाम कोशिशों के उपरान्त भी पार्टी की धड़ेबंदी में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। यही कारण है कि पुराने प्रतिद्वंद्वी सुब्रत मुखर्जी से सुलह के बाद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रिय रंजन दासमुंशी स्थिति संभालने, सुधारने में असफल रहे हैं। एक ओर उन्होंने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण खोया है, दूसरी ओर अशोक सेन और गनी खान चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की बंदूकों का निशाना बने हैं। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक नेता कांग्रेसी अभियान के घोड़ों को विपरीत दिशाओं में दौड़ाने में व्यस्त है। किसी प्रकार की कारगर रणनीति का अभाव पार्टी के रहे-सहे प्रभाव पर भी प्रश्नचिह्न लगाने लगा है। ऐसे समय—'भद्रलोग' छवि वाले प्रणब शायद राज्य की स्थिति पर काबू पा सकें, ऐसी आशा से उनका पुनर्वास करना श्रेयस्कर समझा गया है।

राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी आवश्यकता है, ऐसा पार्टी अध्यक्ष शायद मानने लगे हैं—विशेषकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के विद्रोह के पश्चात। निस्संदेह ही प्रणब मुखर्जी आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की रीति-नीति समझने वाले के रूप में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने वित्तमंत्री काल के दौरान प्रणब विश्व के बेहतरीन वित्तमंत्री होने का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अतः प्रबंधक और विशेषज्ञ के रूप में प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के लिए राजनीति के सैम पित्रोदा सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर तब जब तीन साल से बाहर रह कर वह सभी सीखने योग्य पाठ पढ़ चुके हों—खासकर यह कि राजनीतिक महत्वाकांक्षी को कब लगाम देना है।

हृदय-परिवर्तन का राज : कदाचित प्रणब मुखर्जी को यही जताने के लिए ही उन्हें फिलहाल औपचारिक प्रवेश नहीं दिया गया है। बात स्पष्टतया नाक रगड़वाने की है और दुनिया को यह जताने की कि गरज प्रणब मुखर्जी को अधिक है और कांग्रेस से उनका मिलाप उन राजीव गांधी की शर्तों पर है, जिन्हें कुछ समय पूर्व ही वह खुलेआम ललकार रहे थे। प्रश्न यह है कि प्रणब मुखर्जी का यह हृदय-परिवर्तन हुआ कैसे ?

इसको समझने के लिए प्रणब मुखर्जी के निष्कासन के इतिहास पर एक नजर डालना आवश्यक है। मुखर्जी और उनके समर्थक नेताओं के एक छोटे से गुट को उनकी कथित 'पार्टी विरोधी हरकतों' और नेतृत्व के खिलाफ साजिश के आरोपों के आधार पर इंका से निकाला गया था। इनमें केवल प्रणब और गुंडूराव को ६ वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, जबकि श्रीपति मिश्र, अनंत प्रसाद शर्मा और प्रकाश मेहरोत्रा को निलंबित किया गया था। मिश्र और शर्मा के खिलाफ चल रही कार्रवाई बाद में वापस ले ली गयी थी। विरोध में प्रणब ने एक नयी पार्टी—राष्ट्रीय

समाजवादी पार्टी—का गठन किया। उल्लेखनीय है कि इस पार्टी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्यवाही कभी भी नहीं की। इनमें सबसे प्रमुख नाम अशोक भट्टाचार्य का है जो त्रिपुरा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी। प्रणव मुखर्जी की पार्टी ने मार्च '८७ के पश्चिम बंगाल विधानसभा में इंका का बड़े तामझाम के साथ तगड़ा विरोध किया था, किंतु उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने पर प्रणव मुखर्जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा—वह यह कि इंका के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं। हृदय-परिवर्तन और इंका में वापसी का रास्ता खोजने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी यहीं से हुआ।

यकायक प्रणव मुखर्जी ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व की खामियों को गिनाना बंद कर दिया। यही नहीं, जब राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री विवाद, बोफोर्स और पनडुब्बी घोटालों ने जोर पकड़ा, तो प्रणव ने कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किये बयान को दोहरा कर सरकार, पार्टी और प्रधानमंत्री का पक्ष लिया। हवा का बदला रुख सभी को नजर आने लगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ९ अगस्त, १९८७ को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक गोपनीय बैठक में प्रणव ने एलान किया कि उन्हें कांग्रेस विरोधी अभियान बंद करना चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब-जब कांग्रेसियों ने कांग्रेस का विरोध किया है, तब-तब विपक्ष के हाथ मजबूत हुए हैं। उदाहरण पश्चिम बंगाल का दिया गया, जहां बंगला कांग्रेस के जन्म ने मार्क्सवादियों के हाथ मजबूत किये थे। अब वी०पी० सिंह भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी शक्तियों की सहायता से कांग्रेस की जड़ खोद रहे हैं। अतः पार्टी और देश बचाने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को कांग्रेस विरोध बंद करना होगा।

यही नहीं त्रिपुरा चुनाव की घोषणा होने के पूर्व ही प्रणव ने एलान किया—उनकी पार्टी मार्क्सवादियों का विरोध करेगी और कांग्रेस का समर्थन। अभियान के लिए निमंत्रणपत्र भेजने का इससे अधिक स्पष्ट संकेत कांग्रेस को और क्या हो सकता था।

प्रत्यक्ष संकेतों के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष प्रयासों में भी कोई कमी नहीं रखी गयी। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 'बाबूजी' (कमलापति त्रिपाठी) का वरदहस्त इस गुट के ऊपर से कभी भी पूरी तरह नहीं हटा। यह दूसरी बात है कि बाबूजी का प्रभावक्षेत्र खुद बहुत सीमित रहा है, अतः उसका विशेष लाभ नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री को 'बाबूजी' द्वारा भेजे गये बहुचर्चित पत्र को प्रणब गुट की साजिश का नमूना माना गया था। किंतु उस अपराध की सजा केवल निष्प्रभावी प्रणब गुट को ही दी गयी थी।

विश्वसनीय, सूत्रों के अनुसार बाबूजी के अतिरिक्त प्रभावशाली महासचिव जी०के० मूपनार से भी प्रणब के संबंधों की कड़ी-जुड़ी थी। जानकार लोग इसको प्रणब के पूर्व प्रवेश की महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। जैसा प्रणव के सहयोगी प्रकाश मेहरोत्रा का दावा है, "हम सब कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। परिस्थितियों से विवश हो कर हम कुछ समय के लिए अलग अवश्य हुए, किंतु बाहर रहकर भी हमने कोई पार्टी-विरोधी काम नहीं किया। हमारा झगड़ा पार्टी से था, किसी व्यक्ति-विशेष से नहीं। पार्टी के दिशा-परिवर्तन से ही हम विचलित हुए थे। अतः आज वापस लौटने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।"

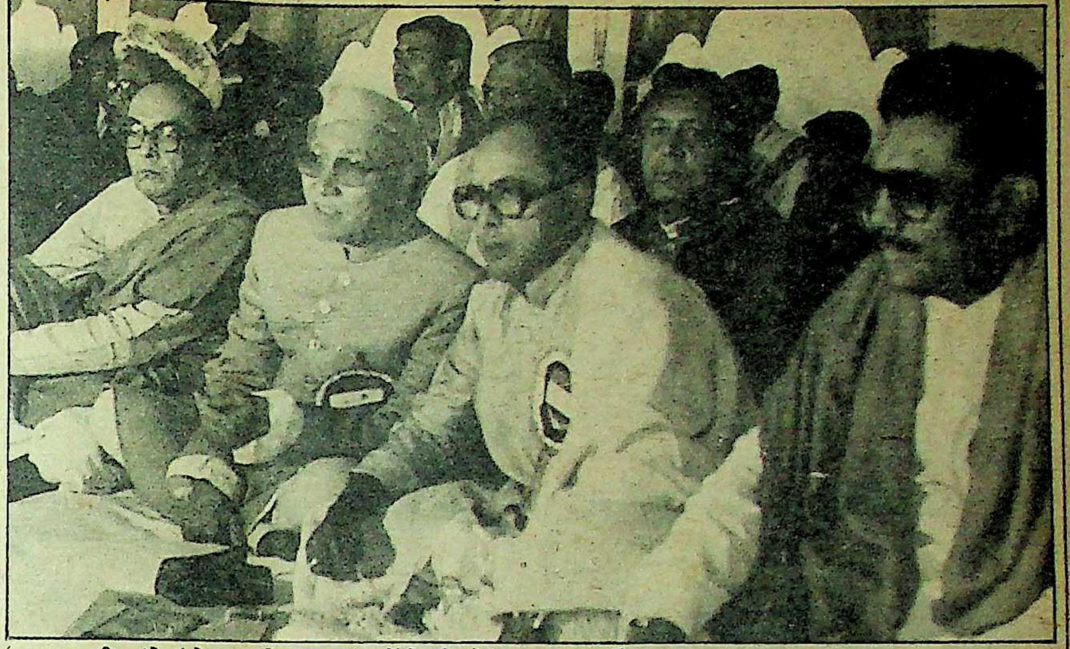

'समाजवादी कांग्रेस' के गठन के समय (बायें से तीसरे) प्रणब मुखर्जी

प्रकाश मेहरोत्रा को न सही, किंतु प्रणब के कुछ अन्य सहयोगियों को प्रणब का यों चोला बदलना जरा भी रास नहीं आया है, जिनमें एफ०एम० खान, डा० शिशिर बोस और एम०एस० महापात्र प्रमुख हैं। उनके विचार से प्रणब यह कदम व्यक्तिगत लाभ के लिए उठा रहे हैं। वह भी पूर्ण आत्मसमपर्ण और अपमान के उपरांत। यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं अथवा कार्यकारिणी की इच्छाओं की अवहेलना की है। पार्टी के संयुक्त सचिव ए०आर० अंसारी और दिलीप चक्रवर्ती का दावा है कि कार्यकारिणी समिति की जिस बैठक में पार्टी को भंग कर उसे कांग्रेस में मिलाने का निर्णय लिया गया, उसमें केवल चार सदस्य ही उपस्थित थे।

कोई विकल्प नहीं: महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी निर्णय इकतरफा हैं। यह बात प्रणब सहित प्रकाश मेहरोत्रा भी स्वीकारते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने न तो फिलहाल उन्हें वापस लिया है, न किसी तरह का आश्वासन ही दिया है। रही मुखर्जी द्वारा त्रिपुरा में चुनाव-अभियान की बात, तो उसके विषय में कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने घोषित किया है कि उसका कोई विशेष महत्व नहीं। पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव-प्रचार में भाग ले सकता है। प्रश्न यह है कि प्रणब ऐसा कर रहे हैं और किस आशा से?

जाहिर है कि प्रणव के पास सत्ता से जुड़ने का फिलहाल अन्य कोई रास्ता नहीं। यदि चुनाव-अभियान में उन्हें सफलता मिलती है, तो कांग्रेस में पुनः प्रवेश पाने में सहायता मिलेगी। किंतु यदि ऐसा न हुआ, तो क्या होगा? कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि ऐसी स्थिति में प्रणब का पूर्ण राजनीतिक वनवास हो जायेगा।

प्रकाश मेहरोत्रा के अनुसार दोनों पक्षों के लिए यह एक पूरी तरह सोचा-समझा कदम है। कदाचित राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को भंग करने की जल्दबाजी भी इसीलिए की गयी है कि कांग्रेस नेतृत्व को प्रणब मुखर्जी की नेकनीयती का भरोसा हो जाये। प्रश्न उठता है कि यदि नेतृत्व को विश्वास हो भी गया, तो क्या अन्य सदस्य विशेषकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रणब मुखर्जी को निष्कंटक प्रवेश पाने देंगे? जाहिर है कि जो बंदूकें आज दासमुंशी की ओर तनी हैं, उनका मुंह प्रणब की ओर हो जायेगा। और प्रणब के पास तो उनका सामना करने के लिए राजनीतिक आधार की भी कमी है। प० बंगाल में पैर जमाने के लिए प्रणब मुखर्जी को निश्चय ही नये समीकरणों का सहारा लेना पड़ेगा।

प्रवेश कब दिया जायेगा इस चर्चा के अतिरिक्त अटकल लगायी जा रही है कि कांग्रेस नेतृत्व उनका (प्रणब का) उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर करेगा। हाल की सूचना के अनुसार प्रणब के अनुभव को मद्देनजर रखकर उन्हें मरणासन्न योजना आयोग को सजीव बनाने का कार्यभार सौंपा जायेगा। किंतु आसानी से नहीं। जो भी होगा उनके अभियान को पूर्णतया चकनाचूर करने के उपरान्त और इस आश्वासन के साथ कि प्रणब अपनी समस्त राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रख चुके हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार में भाग लेने का निमंत्रण दे कर यद्यपि कांग्रेस ने पिछला दरवाजा खोल दिया है, किंतु सामने से अभी भी 'प्रवेश वर्जित' का बोर्ड नहीं हटाया है।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

—रंजना कक्कड़

गैरकांग्रेसी
मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

टकराव की नयी रणनीति

कलकत्ता के बाद एक बार फिर ११ जनवरी '८८ को गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्री बंगलौर में मिले। गैरइंका मुख्यमंत्री जिस तरह से केंद्र के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे केंद्र और प्रांतों के रिश्ते क्या मोड़ लेने जा रहे हैं?

११ जनवरी '८८ को बंगलौर में हुए छह गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र और राजीव गांधी के विरुद्ध कोई खुल्लमखुल्ला नारेबाजी या विद्रोह के तेवर तो नहीं दिखलायी पड़े, लेकिन इस एक दिवसीय सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार कर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देने के लिए जो गुप्त मसविदा तैयार किया गया, उसकी पृष्ठभूमि में छिपा हुआ एक ऐसा तेवर जरूर उजागर हुआ जो भविष्य में केंद्र को राज्यों के बारें में कोई कदम उठाने के पूर्व सोचने के लिए मजबूर अवश्य कर सकता है।

इन छहों राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां यद्यपि अलग-अलग दलों की हैं, लेकिन विरोधी मंच पर ये सभी पार्टियां, कांग्रेस के विरुद्ध एक सुर में बोलती रही हैं। सम्मेलन का आयोजन बंगलौर में ऐसे समय किया गया जब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गैरकांग्रेसी सरकारें (जनता पार्टी तथा तेलुगु देशम पार्टी) अपने शासन के पांच वर्ष पूरे कर रही थीं। यह इत्तफाक था कि सम्मेलन ठीक ऐसे समय हुआ जब एन०टी०आर० ने उच्चन्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। मामला अदालत में होने के कारण खुलकर उच्च न्यायालय के निर्णय को पक्षपातपूर्ण या राजनीति-प्रेरित तो नहीं कहा गया, लेकिन इस मामले में एन०टी०आर० का पूरा समर्थन देने की हामी भरी गयी।

इस सम्मेलन में छहों राज्यों के मुख्यमंत्री-रामकृष्ण हेगड़े (कर्नाटक), एन०टी० रामाराव (आंध्र प्रदेश), ज्योति बसु (प० बंगाल), देवीलाल (हरियाणा), ई० के० नयनार (केरल) तथा प्रफुल्ल मोहंती (असम)—शामिल हुए। नृपेन चक्रवर्ती अस्वस्थता के कारण तथा लालडेंगा और नरबहादुर भंडारी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा छेड़े गये आंदोलन से उत्पन्न अशांति के कारण सम्मेलन में नहीं आ सके। इन्होंने लिखित रूप से सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि गरमी में गुवाहाटी में आयोजित दूसरे सम्मेलन में जरूर शामिल होंगे।

एनटीआर

ज्योति बसु

खुली चर्चा: सम्मेलन में केंद्र-राज्य संबंधों और वित्त आयोग और रिजर्व बैंक की कार्यपद्धति पर खुलकर चर्चा हुई। कर्ज-मेलों के लिए रिजर्व बैंक की अघोपित मंजूरी तथा वित्त आयोग की पक्षपातपूर्ण सिफारिशों ने इन मुख्यमंत्रियों को काफी मर्माहत किया था। देवीलाल ने रिजर्व बैंक को पूंजीपतियों का दलाल तक कह दिया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से ९वें वित्त आयोग के लिए अलग से मसविदे तैयार किये, ताकि प्रधानमंत्री से बातचीत करते समय वे ठीक ढंग से सामने रख सकें। सर्वाधिक आक्रोश वित्त आयोग की कार्यपद्धति को लेकर था। उनके अनुसार आयोग को न्यायपालिका की तरह विष्पक्ष होना चाहिए न कि केन्द्र की मशीनरी जैसा। नवें वित्त आयोग को जिन बातों पर अपना ध्यान मुख्य रूप से केन्द्रित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उनमें राज्यों के विकास-स्तर को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के सही बंटवारे का आकलन करने जैसी मूलभूत समस्याएं नहीं हैं जिनसे राज्यों को हर क्षण दो-चार होना पड़ता है। उनकी शिकायत थी कि वित्त आयोग राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन को दूर करने पर कतई ध्यान नहीं देता, इससे कुछ राज्य तो आर्थिक दृष्टि से साधन-संपन्न होने के बावजूद पिछड़ जाते हैं और कुछ राज्य संपन्न हो जाते हैं। इससे उनमें आपस में कटुता बढ़ती है, जबकि केंद्र इसे राजनीतिक दृष्टि से भुनाता है।

देवीलाल

रामकृष्ण हेगड़े

मुख्यमंत्रियों की एक शिकायत यह भी थी कि केंद्र इस्पात, पेट्रोल, आयातित खाद्य तेल जैसी चीजों के भावों में मनचाही वृद्धि कर राज्यों को मूल्य वृद्धि, मुद्रा संकुचन तथा आर्थिक संकट का बोझ तो उन पर डाल देता है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों से होनेवाली आय में उन्हें शरीक नही करता। वह राज्यों के खर्चों में होनेवाली वृद्धि तथा आर्थिक समस्याओं के लिए उनकी खिचाई भी करता है तथा कड़े कदम उठाने की चेतावनियां भी देता है, लेकिन उनकी मजबूरियों और मौलिक समस्याओं पर न तो ध्यान देता है और न ही आय के लिए नये संसाधन-स्रोतों के बारे में कोई सलाह देता है। रिजर्व बैंक की कार्यपद्धतियों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्रियों का कहना था कि केंद्र ने बिना उनकी मंजूरी लिये ऋण मेले आयोजित कर कई सौ करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिये, लेकिन रिजर्व बैंक ने कोई आपत्ति नहीं की जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा जरूरतमंद किसानों के २४० करोड़ रुपए की कर्जमाफी को नामंजूर कर दिया। फलतः दोनों एक-दूसरे के विरोध में आमने-सामने खड़े हो गये। मुख्यमंत्री सम्मेलन के अनुसार यह गैरकांग्रेसी सरकारों की नकेल थामने की केंद्र, वित्त आयोग और रिजर्व बैंक की मिली-जुली साजिश है।

सुझाव: सम्मेलन ने इससे निजात पाने के लिए अपने मसविदे में जो सुझाव दिये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—राज्यों की हैसियत और खर्च-सीमा को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाये। ओवर ड्राफ्टों की अवधि एक सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह हो। केंद्र सरकार राज्य कर्मचारियों के बढ़े वेतनों की भरपाई करे। केंद्र जिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करे, उसका वाजिब हिस्सा राज्यों को भी दे। राज्यों के बढ़े हुए खर्चों तथा आय पर यथार्थपरक तरीके से विचार कर उन्हें आर्थिक सहूलियतें व सहायता प्रदान करे। राज्यों में शिक्षा सरकारी तथा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में भेदभाव न करके उन राज्यों की उत्पादन व श्रम-क्षमता को ध्यान में रखकर अनुमति दे।

सम्मेलन के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने कहा, "हमने जो मसविदे तैयार किये हैं, वे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और राज्यों के भी हित में हैं। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा, "उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊपर जनता-जनार्दन है न कि वह और अंततः उसी का आदेश सबको मानना पड़ता है।

—विशेष प्रतिनिधि

टवारे का
ं नहीं है
पड़ता है।
ों के बीच
ध्यान नहीं
से साधन-
और कुछ
आपस में
क दृष्टि से

भी थी कि
सी चीजों
ूल्य वृद्धि,
ो उन पर
होनेवाली
ों के खर्चों
ों के लिए
दम उठाने
उनकी
तो ध्यान
-स्रोतों के
बैंक की
ख्यमंत्रियों
ूरी लिये
रुपए बट्टे
ई आपत्ति
चौधरी
० करोड़
। फलतः
ो खड़े हो
रकांग्रेसी
आयोग
है।
पाने के
उनमें से
ौर खर्च-
। ओवर
ाय तीन
ों के बढ़े
ुओं की
ा राज्यों
आय पर
आर्थिक
में शिक्षा
ापना में
व श्रम-

ख्यमंत्री
दि तैयार
ों के भी
ए कहा
ो ऊपर
उसी का

तिनिधि

हर महफ़िल में रंग जमा दे!
McDowell's
DIPLOMAT
DIPLOMAT
McDowell's
DIPLOMAT
COLOGNE

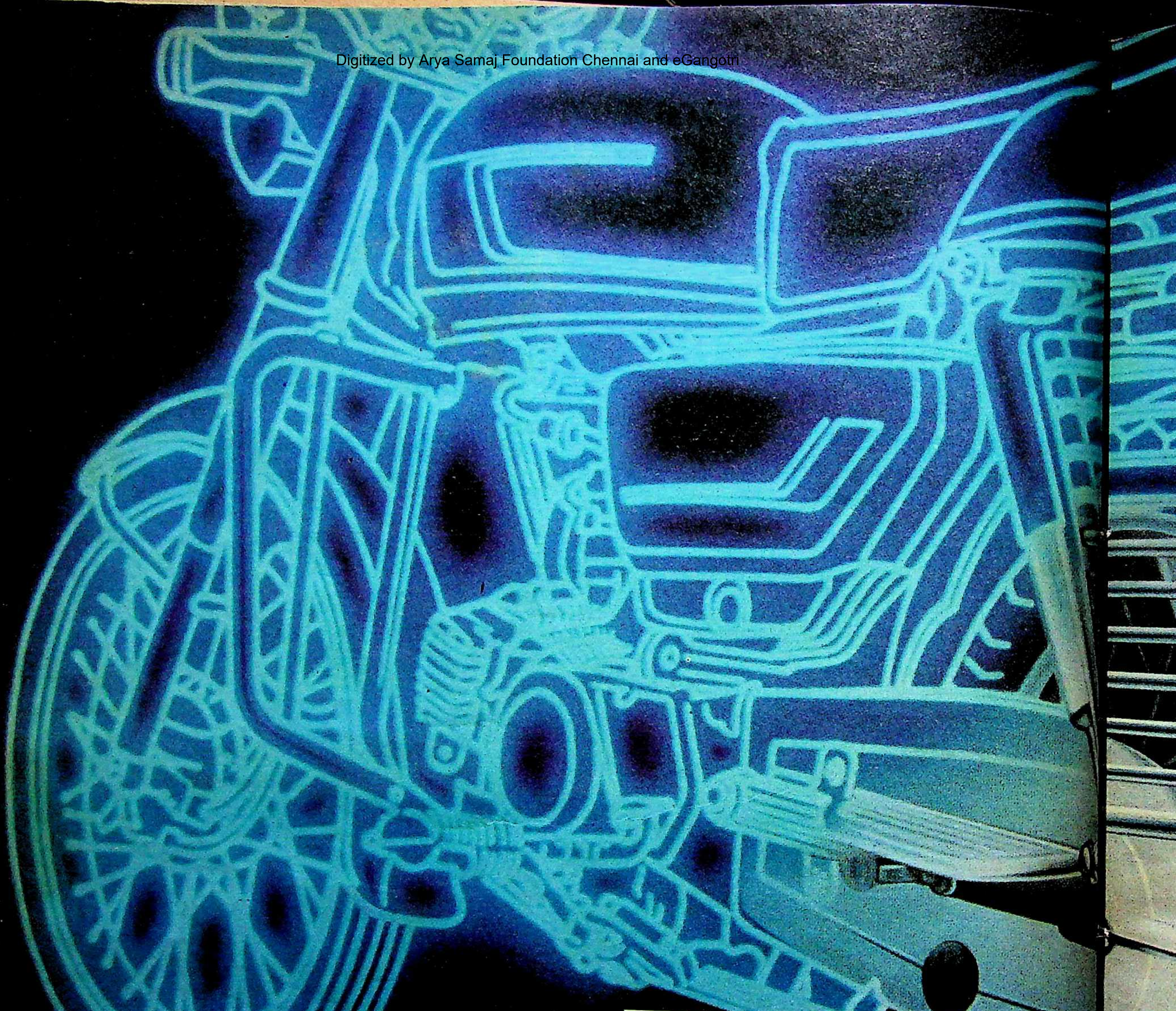

सड़क पर पूरी पकड़

जबरदस्त पकड़ का भरोसा. घुमावदार मोड़ हों या ढालदार ढलानें. या फिर ऐसी सड़कें जिनकी जान-पहचान तक न हो.

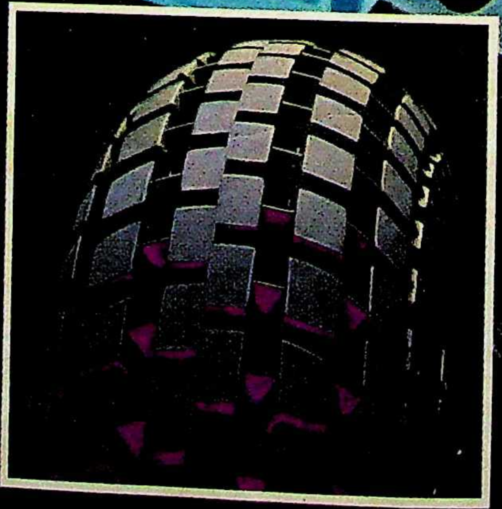

तुरंत ब्रेकिंग

जब न समय हो न दूरी, इसका विशेष डिज़ाइन फौरन ब्रेक लगाने के लिए ही बना है.

सतह पर नियंत्रण

इसका विशेष सिएट ट्रॅड पैटर्न गीली-फिसलनी-दलदली सड़कों पर भी पकड़ नहीं छोड़ता. फिसलन से पूरा बचाव.

सिएट मोटरसाइकल टायर...

जापानी उत्तमता

योकोहामा रबड़ कंपनी, जापान, के सहयोग से टायर तकनीक में सब से आधुनिक भेंट. हर मोटरसाइकल के लिए. बुलेट से लेकर येज़दी तक. या फिर नई पीढ़ी की हिरो-हॉन्डा, बजाज कावासाकी और राजदूत यामाहा के लिए. इसलिए सिएट मोटरसाइकल टायर ही मांगिए... हमेशा.

...क्योंकि सिएट ही सर्वोत्तम टायर बनाते हैं.

CEAT

बॉर्न टफ

नरेंद्र हीरवानी का करिश्मा

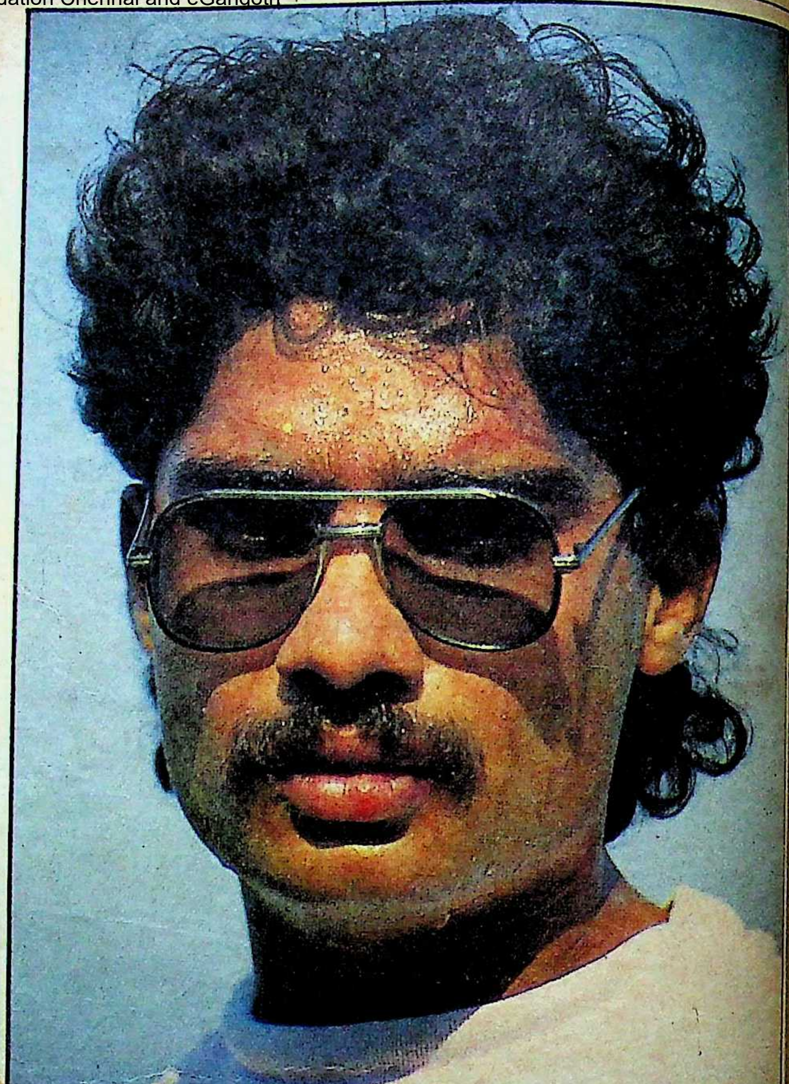

अब तो लगता है वह अलौकिक स्वप्न था या दैवी चमत्कार जो मद्रास टेस्ट में नरेंद्र हीरवानी ने किया। लेग स्पिनर के रूप में शिवरामकृष्णन जब भारतीय टीम में शामिल हुआ था, तो उसने भी पहले टेस्ट में अपनी लेग स्पिन गेंदों का जादू दिखाया था, पर बाद के मैचों में लगातार मौका दिये जाने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाया और इस तरह एक प्रतिभा दब गयी। नरेंद्र हीरवानी ने भी मद्रास टेस्ट में करिश्मा दिखाया जो विश्व रिकार्ड बन गया है, पर त्रिवेंद्रम और बंबई में खेले गये एक दिवसीय मैच में उसे एक भी विकेट नहीं मिला। उसकी गेंदबाजी में वह पैनापन भी नहीं था जो मद्रास टेस्ट में देखने को मिला था। पहले ही टेस्ट में विश्व रिकार्ड बनाने वाले नरेंद्र हीरवानी की क्रिकेट-यात्रा और उपलब्धियों पर रपट :

छाया : बिंदु अरोड़ा

छाया : शरद पंडित

१९ वर्ष का चश्माधारी एक क्रिकेटर पैवेलियन में बैठा अपने साथी खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ियों के आगे असहाय होते देखता रहा। पर वह कर भी क्या सकता था? टीम में तो वह था, पर ग्यारह खिलाड़ियों में कहीं नहीं था। दो टेस्ट मैचीं तक ड्रेसिंग रूम से पैवेलियन तक सीमित रहे उस क्रिकेटर को मद्रास टेस्ट में तब मौका मिला, जब मनिंदर सिंह घायल होने के कारण खेलने योग्य नहीं रहे। मद्रास टेस्ट में जब भारतीय टीम के साथ यह क्रिकेटर मैदान पर एक लेग स्पिनर के रूप में उतरा, तो भी लोगों ने इस खिलाड़ी को एक खानापूर्ति के रूप में लिया। इस क्रिकेटर को गेंद मिली और उसने वेस्टइंडीज की पारी में गेंद डालनी शुरू की और फिर उसने एक के बाद एक पहली पारी में आठ विकेट और फिर दूसरी पारी में आठ विकेट लेकर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाजों को 'आयाराम गयाराम' के तर्ज पर विदा ही नहीं किया, बल्कि भारत को मद्रास टेस्ट में विजय दिलाकर टेस्ट शृंखला बराबर भी कर दी। यह खिलाड़ी था नरेंद्र हीरवानी, जिसने अपनी सफलता को विश्वरिकार्ड बना दिया।

क्रिकेट और संयोग एक दूसरे के पर्याय हैं। पर कोई बड़ा संयोग हो जाये, तो वह जादू से कम नहीं माना जा सकता। १५ जनवरी, १९८८-मद्रास का चेपक स्टेडियम और नरेंद्र हीरवानी-क्रिकेट-इतिहास के एक ऐसे अध्याय बन गये हैं जो अपनी स्वर्णिम चमक के कारण बराबर याद किये जायेंगे। १५ साल ६ महीने और २१ दिन पहले क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लार्ड्स मैदान पर जो करिश्मा बाब मैसी ने दिखाया था, वैसा ही करिश्मा १५ जनवरी, १९८८ को भारत के लेग स्पिनर नरेंद्र हीरवानी ने दिखाया। लार्ड्स टेस्ट बाब मैसी का पहला टेस्ट था, तो मद्रास टेस्ट नरेंद्र हीरवानी के लिए। पहले टेस्ट में बाब मैसी आस्ट्रेलियाई टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, तो नरेंद्र हीरवानी भी अपने पहले टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम (१९ वर्ष) उम्र के खिलाड़ी रहे। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि हीरवानी ने मद्रास टेस्ट में चौथे दिन जब वेस्टइंडीज के डेविस को विकेट कीपर किरण मोरे के हाथों स्टंप कराकर अपनी झोली में १६वां विकेट डाला, तो समय था-२ बजकर ३५ मिनट। इसी तरह १५ वर्ष ६ महीने और २१ दिन पहले लार्ड्स के मैदान पर चौथे दिन बाब मैसी ने

जब इंग्लैंड का सोलहवां विकेट लिया, तो उस समय भी घड़ी में समय था-२ बजकर ३५ मिनट।

एक ही समय में एक जैसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बाब मैसी ने अपने पहले ही टेस्ट में १६ विकेट १३७ रन देकर लिये, तो नरेंद्र हीरवानी ने इस उपलब्धि को १३६ रन देकर प्राप्त किया। इस तरह हीरवानी बाब मैसी से इसलिए आगे निकल गये कि उसने एक रन कम दिया।

लगन: सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचने वाला नरेंद्र हीरवानी (जन्म १८ अक्तूबर, १९६८) जब अपने गृहनगर गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से मैच खेलने इंदौर (मध्य प्रदेश) आया, तो वहां की आबोहवा, माहौल और संजय जगदाले के प्रोत्साहन ने उसे इंदौर में ही बस जाने के लिए विवश कर दिया। पर उस समय नरेंद्र हीरवानी इतना मोटा था कि उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसमें लगन थी, एक अच्छा खिलाड़ी बनने की और इसके लिए उसने पहले अपना वजन १६ किलो कम किया। अपने पिता के ईंट के भट्ठों के व्यापार को छोड़ा और अपने परिवार से दूर रहा। इंदौर आने पर हीरवानी का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि वह दूसरे प्रदेश का था, पर संजय जगदाले उसकी प्रतिभा को पहचान चुके थे—इसलिए उनकी देखरेख में हीरवानी ने विरोधों की परवाह न करते हुए अपना नियमित अभ्यास जारी रखा। उसका अभ्यास दिन-ब-दिन उसकी प्रतिभा को निखारता रहा। १९८५ में उसने रणजी ट्राफी खेली और मध्य क्षेत्र की लीग स्पर्धा के ४ मैचों में उसने २४ विकेट लिये। १९८५ में आस्ट्रेलिया गये भारत की युवा टीम में हीरवानी भी शामिल था। इस दौर में उसने तीन टेस्ट मैचों में २३ विकेट लिये।

पाकिस्तान की टीम के खिलाफ बोर्ड प्रेसीडेंट टीम के लिए उसने बढ़िया गेंदबाजी की। दिलीप ट्राफी और ईरानी ट्राफी में भी उसकी गेंदबाजी उसकी प्रतिभा की परिचायक रही। इन उपलब्धियों के बावजूद नंबर एक मैचों में उसको मौका नहीं दिया गया। देवधर ट्राफी में उसे लिया तो गया, पर ड्रेसिंग रूम तक ही वह सीमित रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ चंडीगढ़ में जब उसने भारतीय युवा टीम की ओर से खेलते हुए दूसरी पारी में छह विकेट लिये, तब उसकी ओर क्रिकेट चयनकर्ताओं की निगाहें उठीं। इसके बाद उसे भारतीय टीम में शामिल किया गया। दो टेस्ट मैचों में तो वह ड्रेसिंग रूम तक ही था, लेकिन मद्रास टेस्ट में उसे मौका मिला। भारत के लिए टेस्ट खेलने—का सपना उसने वर्षों से संजो रखा था और इस स्वप्न के साकार होते ही उसे वह सम्मान मिला जो नसीबवालों को ही मिलता है।

रिकार्ड-दर-रिकार्ड: मद्रास टेस्ट की पहली पारी में नरेंद्र हीरवानी ने रिची रिचर्ड्सन को मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों कैच करवा कर अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। लोगी को भी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नरेंद्र हीरवानी की गेंद पर कैच पकड़कर पैवेलियन की राह दिखायी। ३५ रन पर ३ विकेट लेने पर भी नहीं लग रहा था कि हीरवानी किसी चमत्कार की ओर बढ़ रहा है या वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए वह आतंक बन जायेगा।

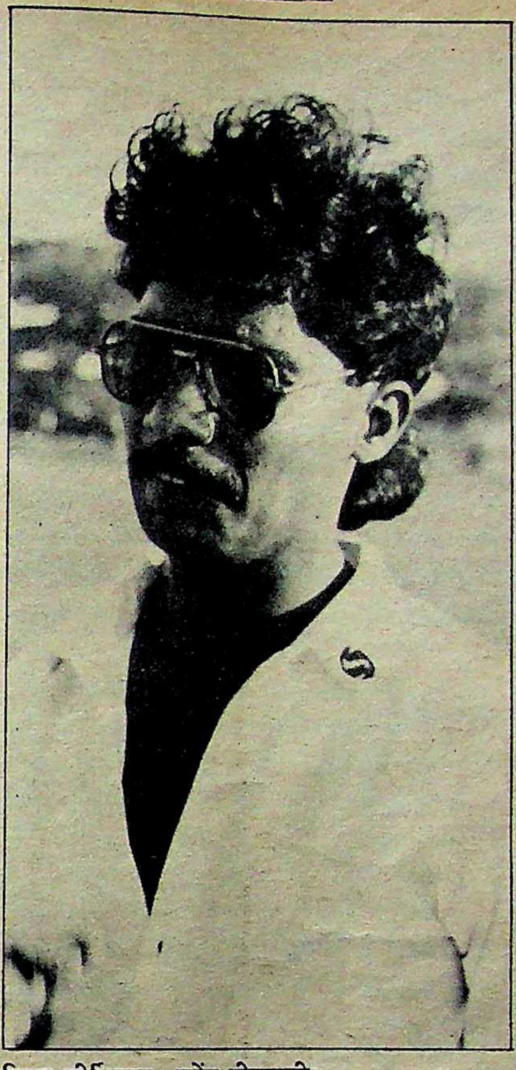

विश्व कीर्तिमान: नरेंद्र हीरवानी

एक दिन के विश्राम के बाद जब हीरवानी गेंद फेंकने आया, तो उसके सामने थे—वेस्टइंडीज के कप्तान विव रिचर्ड्स जो दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नरेंद्र हीरवानी की गेंदों को बहुत ही सहजता से खेल रहे थे। विश्राम के दिन के बाद अगले दिन हीरवानी ने गेंद फेंकी और रिचर्ड्स क्लीन बोल्ड हो गये। रिचर्ड्स जैसा बल्लेबाज जिस तरह आउट हुआ, उससे लगा कि हीरवानी ने एक दिन के विश्राम में अपनी रणनीति तय कर ली थी। रिचर्ड्स का आउट होना, भावी करिश्मे का संकेत था और फिर संकेत तेजी से चमत्कार में बदल गया।

एक दिन के विश्राम के बाद जब हीरवानी गेंद फेंकने आया, तो उसके सामने थे—वेस्टइंडीज के कप्तान विव रिचर्ड्स जो दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नरेंद्र हीरवानी की गेंदों को बहुत ही सहजता से खेल रहे थे। विश्राम के दिन के बाद अगले दिन हीरवानी ने गेंद फेंकी और रिचर्ड्स क्लीन बोल्ड हो गये। रिचर्ड्स जैसा बल्लेबाज जिस तरह आउट हुआ, उससे लगा कि हीरवानी ने एक दिन के विश्राम में अपनी रणनीति तय कर ली थी। रिचर्ड्स का आउट होना, भावी करिश्मे का संकेत था और फिर संकेत तेजी से चमत्कार में बदल गया। हीरवानी ने ६१ रन पर ८ विकेट प्राप्त कर लिये थे।

नरेंद्र हीरवानी की इस उपलब्धि (एक पारी में ८ विकेट) के पहले कुछ ही ऐसे गेंदबाज हुए जिन्होंने एक पारी में ९ विकेट लेने का करिश्मा दिखाया था। इंग्लैंड के जिम लेकर ने तो एक पारी में १० विकेट लिये थे। अपने यहां १९५९-६० में जसु पटेल ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ ६९ रन देकर ९ विकेट लिये थे। इसके पूर्व वेस्टइंडीज के साथ कानपुर में खेले गये एक मैच में सुभाष गुप्ते ने १०२ रन देकर ९ विकेट प्राप्त किये थे। १९८३ में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ कपिल देव ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में ८३ रन देकर ९ विकेट प्राप्त किये थे। ये सब ऐसे खिलाड़ी थे, जो पूर्व में कई टेस्ट खेल चुके थे, हीरवानी की उपलब्धि इनसे बीस इसलिए रही, क्योंकि वह पहले टेस्ट में अधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज हो गया। हीरवानी से पहले आबिद अली और दिलीप दोषी ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले ही टेस्ट में ६-६ विकेट लिये थे। आबिद अली ने १९६७-६८ में आस्ट्रेलिया के खिलाफ ५५ रन पर ६ विकेट और १९७९-८० में दिलीप दोषी ने पाकिस्तान के खिलाफ ११४ रन पर ६ विकेट प्राप्त किये थे।

दुनिया के गेंदबाजों को तलाशा जाये, तो बाब मैसी के अलावा क्रिकेट के ११० वर्ष के टेस्ट इतिहास में दो ही ऐसे गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने पहली ही पारी में ८ विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया। आस्ट्रेलिया के ए० ईट्राट ने १८९४-९५ में इंग्लैंड के खिलाफ ४३ रन पर ८ विकेट लिये थे और १९५० में मानचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर वेस्टइंडीज के ए०एल० वैलेंटाइन ने पहले ही टेस्ट में १०४ रन पर ८ विकेट प्राप्त किये थे। बाब मैसी इस कड़ी के तीसरे गेंदबाज थे और अब चौथी कड़ी के रूप में हीरवानी का नाम सामने है। हीरवानी के अलावा एक पारी में ८ विकेट लेने वाले विश्व के ५९ गेंदबाजों में चार गेंदबाज भारत के हैं। ये चारों स्पिन गेंदबाज थे।। वीनू मांकड़ ने एक पारी में ८ विकेट लेने का करिश्मा दो बार किया था। उन्होंने १९५१-५२ में इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास में ५५ रन पर ८ विकेट और फिर १९५२-५३ में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में ५२ रन पर ८ [illegible]

थे। वेंकटराघवन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल्ली में ७२ रन पर ८ विकेट और दिल्ली में ही इंग्लैंड के खिलाफ चंद्रशेखर ने ७९ रन पर ८ विकेट हासिल किये थे। इरापल्ली प्रसन्ना ने आकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ ७६ रन पर ८ विकेट लिये थे। हीरवानी इस कड़ी में अलग इसलिए है, क्योंकि उसने यह उपलब्धि अपने टेस्ट क्रिकेट जीवन की पहली पारी में ही हासिल की।

नरेंद्र हीरवानी ने दूसरी पारी में सीमंस का जब विकेट लिया, तो क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों को लगा कि हीरवानी का जादू फिर चलेगा। हेंस, रिचर्ड्स और हूपर के विकेट लेकर उसने इस बात के संकेत दे दिये कि आज का दिन भी उसी का है। जैसे ही हीरवानी ने १२ वां विकेट प्राप्त किया, दो रिकार्ड टूट गये। इसके पहले १९६६-६७ में बंबई में चंद्रशेखर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ २३५ रन पर ११ विकेट और १९३३ में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के सी० मैरियर ने ९६ रन पर ११ विकेट लिये थे। हीरवानी ने जब १३ वां विकेट लिया, तो एंडी रावर्ट्स के १२१ रन पर १२ विकेट का रिकार्ड तोड़ दिया। १४ वां विकेट लेते ही हीरवानी ने टोनी ग्रेग का १९७३-७४ में बनाया १५६ रन पर १३ विकेट का रिकार्ड तोड़ दिया। १५ वां विकेट प्राप्त करते ही हीरवानी ने माइकल होल्डिंग के (१४९ रन पर १४ विकेट) रिकार्ड को केवल तोड़ा ही नहीं, बल्कि भारत के एक टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज भी बन गया। लगभग २८ वर्ष पूर्व १९५९-६० में कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर जसु पटेल ने १२४ रन पर १४ विकेट लेने का रिकार्ड बनाया था, जिसे हीरवानी के पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज तोड़ नहीं सका था। १६वें विकेट ने तो हीरवानी को बाव मैसी के विश्व रिकार्ड की बराबरी तक पहुंचा दिया।

बाव मैसी ने १९७२ (२२ से २६ जून) में आस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी खेलते हुए दोनों पारियों में ८-८ विकेट प्राप्त किया था और यह विश्व कीर्तिमान था। बाव मैसी ने १३७ रन देकर कुल १६ विकेट लिये थे। १५ जनवरी, १९८८ तक यह विश्व कीर्तिमान सभी गेंदबाजों के लिए चुनौती था। हीरवानी ने १३६ रन पर १६ विकेट लेकर इस कीर्तिमान को पार कर लिया। हीरवानी इस रिकार्ड को तोड़कर दुनिया के उन तीन गेंदबाजों में शामिल हो गया है, जिन्होंने किसी भी टेस्ट में १६ या उससे अधिक विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया है। इंग्लैंड के जिम लेकर ने १९५६ में मानचेस्टर के मैदान पर केवल ९० रन देकर आस्ट्रेलिया के २० में से १९ विकेट लिये थे। इसी तरह एस०एफ० बार्न्स ने १९१३-१४ में योहानीसवर्ग में इंग्लैंड की ओर से

साक्षात्कार/ नरेन्द्र हीरवानी

मैं आल राउंडर बनना चाहता हूं

हीरू से अचानक हीरो बने नरेन्द्र हीरवानी की इच्छा है कि वह आलराउंडर क्रिकेटर बनें। इस दिशा में वह प्रयासरत भी हैं। दूसरी ओर वह अपने दायें हाथ के लेग स्पिन चमत्कार को भी निखारना चाहते हैं। सफलता का श्रेय अपने प्रशिक्षक संजय जगदाले को देने वाले हीरवानी मानते हैं कि अगर सर न मिले होते, तो वह आज इस स्थिति में न होते। सहज और सौम्य दिखने वाले नरेन्द्र हीरवानी से बेबाक बातचीत के अंश:

माया: आपके पिताजी व्यापारी हैं और वह आपको अपने पारिवारिक ईंटों के भट्टे के व्यवसाय की ओर ले जाना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति में क्रिकेट के प्रति आपका लगाव कब और क्यों हुआ?

हीरवानी: क्रिकेट के प्रति बचपन से ही मेरे मन में लगाव रहा। बचपन से ही मैं स्कूल जाने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता था। मुझे तब अजीब सा सुकून क्रिकेट खेलते हुए मिलता था। वह सुकून मुझे व्यापार में नहीं मिल सकता।

माया: अपना गृहनगर गोरखपुर छोड़कर आपने इन्दौर में क्रिकेट खेलना क्यों पसंद किया?

हीरवानी: आज से कोई छह साल पहले मैं उत्तर प्रदेश की पंद्रह वर्ष से कम आयु की टीम में क्रिकेट खेलने इन्दौर आया था। तब मुझे इन्दौर आकर लगा कि यहां क्रिकेट खेलने और प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, तो मैंने इन्दौर आने का फैसला कर लिया। इस संबंध में मैंने क्रिकेट क्लब इन्दौर के प्रशिक्षक श्री संजय जगदाले से बात की, तो उन्होंने न केवल मेरा उत्साह बढ़ाया, बल्कि मेरे लिए इन्दौर में व्यवस्था भी कर दी। श्री जगदाले से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसा प्रशिक्षक तलाश रहा था, वैसे प्रशिक्षक यही हैं।

माया: दायें हाथ की स्पिन गेंदबाजी की प्रेरणा आपको कहां से मिली और कब से इस दिशा में प्रयासरत हैं? क्या आपको भरोसा था कि आप सफल होंगे?

हीरवानी: स्पिन गेंदबाजी शुरू से ही मेरा ध्येय रहा है। मुझे लगता था कि मैं इस दिशा में तरक्की कर सकता हूं। इसी आत्मविश्वास के सहारे मैंने यह सफलता पायी। इस सफलता के बाद भी मैं अपने आपको और निखारने के लिए प्रयासरत हूं।

माया: आपके अभ्यास का नियमित क्रम है?

हीरवानी: सामान्यतः सुबह व्यायाम और रनिंग के बाद तीन घंटे नेट प्रैक्टिस करता इसके बाद शाम को कोई चार घंटे गेंदबा का अभ्यास करता हूं।

माया: आप अपनी सफलता का श्रेय किसे हैं?

हीरवानी: मेरी सफलता का पूर्ण श्रेय सर (श्री संजय जगदाले) को है, जिन्होंने रा दिन एक करके मुझे इस स्थिति में ला दि अगर सर (श्री जगदाले) न होते, तो शा मैं इतनी बड़ी सफलता न पा सकता।

माया: मद्रास टेस्ट में आपकी सफलता के लिए विवियन रिचर्ड्स ने स्पिन विकेट को ज्यादा श्रेय दिया है। इस बारे में आपका खयाल है?

हीरवानी: मैं वेस्टइंडीज के कप्तान की इ बात से काफी सहमत हूं कि विकेट से मुझे काफी मदद मिल रही थी, पर यही मेरी सफलता का एकमात्र कारण नहीं है।

माया: आज क्रिकेट में आलराउंडर क्रिकेट युग है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी आलराउंडर बनें?

हीरवानी: निश्चित तौर पर मैं आलराउं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूं। इसके लिए मैं लगातार प्रयास भी कर रहा हूं।

माया: क्रिकेट में आपका आदर्श कौन है?

हीरवानी: पाकिस्तान के मशहूर लेग स्पिन अब्दुल कादिर मेरे आदर्श हैं। मैं उन्हीं के नक्शेकदम पर आगे बढ़ना चाहता हूं।

माया: एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और टेस्ट मैच में से आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे?

हीरवानी: मैं दोनों तरह के मैचों को समा

खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के १५९ रन पर १७ विकेट झटके थे। और अब इनके बाद हैं, नरेंद्र हीरवानी।

जिम लेकर का रिकार्ड तो अभी तक अटल है। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिम लेकर तेज गेंदबाज नहीं, आफ स्पिनर थे। उनके खिलाफ मैक्डोनल्ड, वर्क, नील हार्वे, कीथ मिलर और रिची बेनो जैसे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे। जिम लेकर ने पहली पारी में १६.४ ओवर फेंके जिसमें ४ मेडन थे। ३७ रन देकर उन्होंने ९ विकेट लिये। दूसरी पारी में उन्होंने ५१.२ ओवर फेंके जिसमें से २३ मेडन ओवर रहे और ५३ रन देकर १० विकेट लिये। १९५६ (२६ से ३१ जुलाई) में खेला गया यह टेस्ट जिम लेकर के मैच के रूप में विख्यात है।

१९१३ (२६ से ३० दिसंबर) को योहानीसबर्ग में इंग्लैंड की ओर से बार्न्स ने पहली पारी में २६.५ ओवर गेंदें फेंकी जिसमें ९ ओवर मेडेन रहे और ५६ पर ८ विकेट मिले। दूसरी पारी में ३८.७ ओवर में ७ मेडन फेंककर १०३ रन पर ९ विकेट प्राप्त किये थे। यह दूसरा विश्व रिकार्ड है। अब तीसरा विश्व रिकार्ड है— नरेंद्र हीरवानी का। हीरवानी ने दोनों पारियों में ३३.५ ओवर फेंके, जिसमें ७ ओवर मेडन रहे और १३६ रन देकर उसने १६ विकेट प्राप्त किये। इस तरह विश्व के चार गेंदबाजों में हीरवानी ने सबसे कम ओवर फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की। इसे भी एक विश्व रिकार्ड माना ज़ा सकता है। मेडन ओवर घटा दिये जायें, तो यह उपलब्धि और बड़ी हो जाती है।

जिस तरह १९५६ में ओल्ड ट्रैफर्ड (मानचेस्टर) में खेला गया मैच 'जिम लेकर का मैच' और १९७२ में लार्ड्स पर खेला गया मैच 'बाब मैसी का मैच' के रूप में जाना जाता है, उसी तरह मद्रास टेस्ट (१५ जनवरी, १९८८) नरेंद्र हीरवानी के नाम से विश्व क्रिकेट में याद किया जायेगा, इसमें कोई शक नहीं है।

छोटी उम्र में जो बड़ी सफलता हीरवानी ने हासिल की है, क्या उसे वह बरकरार रख पायेगा या शिवरामकृष्णन जैसी उसकी भी स्थिति होगी, क्योंकि हीरवानी के इस सफलता से लोगों की यही उम्मीद रहेगी कि वह हमेशा करिश्मा दिखाये। यह ऐसा दबाव होता है कि ब़ड़े-बड़े खिलाड़ी असहाय से हो जाते हैं। शिवरामकृष्णन इसके उदाहरण हैं। अपने दूसरे ही टेस्ट में बंबई में इंग्लैंड के खिलाफ १९८४-८५ में उसने ११ विकेट लिये। १९८५ में आस्ट्रेलिया में हुए सात देशों के एक दिन के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वहां भारत की जीत का आधार शिवरामकृष्णन बने। १९ वर्ष की उम्र में ही उसने यह सफलताएं और ख्याति अर्जित की, लेकिन आज टेस्ट टीम में तो उसे लेने की बात ही नहीं होती है। रणजी ट्राफी के मैचों में भी वह पहले जैसी सफलता पाने को तरस जाता है। विव रिचर्ड्स ने मद्रास ट्रेस्ट हारने के बाद कहा कि पिच ने हीरवानी का साथ दिया। मतलब यह है कि हीरवानी ने कमाल कम किया, पिच ने अधिक। यदि ऐसा रहा, तो अब्दुल कादिर को अपना प्रेरणास्रोत मानने वाले हीरवानी को यह समझना पड़ेगा कि हर पिच उसका साथ नहीं देगी। अब्दुल कादिर की तरह हर पिच पर अपना आतंक दिखाने के लिए उसे अपनी गेंदों में पैनापन लाना होगा। विव रिचर्ड्स के कहे वाक्य में सचाई इसलिए नजर आती है, क्योंकि त्रिवेंद्रम और बंबई में खेले गये एक दिवसीय मैचों में नरेंद्र हीरवानी एक विकेट पाने के लिए तरस गया और बंबई में तो उसकी गेंदों की वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने धुनाई करके रख दी।

हीरवानी इस समय उम्र और सफलता दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोत्तम पड़ाव पर है, परंतु भविष्य में उसकी सफलता उसकी मेहनत पर ही निर्भर करेगी।

—दिनेश दीनू

> विव रिचर्ड्स ने मद्रास टेस्ट हारने के बाद कहा कि पिच ने हीरवानी का साथ दिया। मतलब यह है कि हीरवानी ने कमाल कम किया, पिच ने अधिक। यदि ऐसा रहा, तो अब्दुल कादिर को अपना प्रेरणास्रोत मानने वाले हीरवानी को यह समझना पड़ेगा कि हर पिच उसका साथ नहीं देगी। अब्दुल कादिर की तरह हर पिच पर अपना आतंक दिखाने के लिए उसे अपनी गेंदों में पैनापन लाना होगा।

प से पसंद करता हूं। दोनों तरह के मैचों अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए दोनों में से सी के महत्व को कम करके नहीं आंका जा कता।

या: क्रिकेट में मिली इस आशातीत फलता के बाद आप अपने क्रिकेट भविष्य के रे में क्या उम्मीद रखते हैं?

रवानी: यह तो आने वाला वक्त बतायेगा।

या: मद्रास में किस खिलाड़ी का विकेट लेते ए आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई?

रवानी: मुझे सर्वाधिक खुशी विवियन चर्ड्स का विकेट लेते हुए हुई। निश्चित ही र लिए वह अविस्मरणीय क्षण था।

या: क्रिकेट सितारा बनने के बाद र्वजनिक समारोहों की चकाचौंध क्या आपके ल को प्रभावित नहीं करेगी?

रवानी: सार्वजनिक समारोहों में व्यस्तता श्चित ही, क्रिकेट पर प्रभाव डालेगी। मैं शिश कर रहा हूं कि कम-से-कम समारोहों हिस्सा लूं, पर कुछ सार्वजनिक दायित्व तो करने ही पड़ते हैं।

या: क्रिकेट के साथ क्या आप पढ़ाई के ए वक्त निकाल पाते हैं?

रवानी: इस वर्ष गहन प्रशिक्षण के कारण ढ़ाई तो बिलकुल भी नहीं कर पा रहा हूं। दौर के क्रिश्चियन कालेज में जहां मैंने ०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, वहां भी मुश्किल जा पाता हूं। मुझे आज तक पता हीं कि मेरी कक्षा में कितने और कौन छात्र ?

या: क्रिकेट के अलावा आपके और क्या क हैं?

रवानी: क्रिकेट के अलावा बचे समय में मैं हम्मद रफी के गीत सुनना बेहद पसंद रता हूं।

—शिवअनुराग पटरैया

अपने प्रशिक्षक की नजर में

नरेंद्र हीरवानी को प्रतिदिन चार-पांच घंटे प्रशिक्षण देने वाले उसके प्रशिक्षक संजय जगदाले का कहना है:

जब पहली बार हीरवानी मेरे पास आया था, तो इतना मोटा था कि मैंने उसे मना कर दिया था कि तुम क्रिकेट नहीं सीख सकते। लेकिन उसे मुझसे सीखने की जिद थी। उसने कहा था कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। उसका लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे रणजी या दिलीप ट्राफी में खेलना है। उसका लक्ष्य हमेशा भारतीय टीम में खेलना रहा और वह अपने लक्ष्य में एक दिन सफल हुआ। उसकी क्रिकेट के अलावा पहले भी कोई रुचि नहीं थी। वह क्रिकेट के प्रति पूणत: समर्पित है।

मेरे खयाल से अभी यह लड़का काफी दूर (ऊंचाई) तक जा सकता है और जायेगा। मद्रास टेस्ट खतम होने के बाद वह अगले दिन इंदौर आया था और अपनी गेंदबाजी के कैसेटों को तल्लीनता से देखता रहा था कि उसने कब, कहां, कौन-सी गलती की? वह उत्साह से बताता जा रहा था कि उसने किस तरह से गेंद फेंकी और उसे कैसे विकेट मिले? उसको उस वक्त देखने से यही लगता था कि उसमें अभी और सीखने की वैसी ही लगन है, जैसी चार साल पहले थी। नरेंद्र की मद्रास टेस्ट में उपलब्धि पर मुझे इतनी अधिक प्रसन्नता हुई थी कि मैं अपनी खुशी को जज्ब नहीं कर पा रहा था।

—एस०पी० त्रिपाठी

हाकी से राजनीति का रंग कब उतरेगा ?

इंदिरा स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता याद रखी जायेगी खेल पर राजनीतिज्ञों के बढ़ते प्रभाव के रूप में। इस प्रतियोगिता में मेहमानों की सुख-सुविधाओं की अनदेखी हुई और शाहिद जैसे खिलाड़ियों को अपमानित होना पड़ा। दूसरी तरफ नेताओं और अफसरों ने चांदी पीटी।

ध्यान चन्द स्टेडियम

अब खेल मैदानों में भी होती है राजनीति

Sahara India

एशियायी शैली में खेलकर पाकिस्तान ने यूरोपीय हाकी के छक्के छुड़ा दिये

खेलों में राजनीति का घुन तो काफी पहले से ही लगा हुआ था। अब राजनीतिज्ञों की खेलों में व्यापक घुसपैठ से खेल मंदिर का माहौल काफी गंदा हो गया है। राजनीतिज्ञों को खुश करने की महामारी से कई प्रतियोगिताओं और कई स्टेडियमों का नाम तक उन पर रखा जा चुका है। राजनीतिज्ञों के नाम से चली कई खेल प्रतियोगिताओं की अकाल मौत भी देखी गयी है, पर इंदिरा गांधी के नाम से शुरू इंदिरा गांधी स्मारक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता ने अपने दूसरे ही वर्ष में अपना रुतबा और बढ़ा लिया है।

८ जनवरी, १९८८ से १६ जनवरी, १९८८ तक लखनऊ में संपन्न द्वितीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी में जैसी हलचल हुई उसको देखते हुए ही अंतरराष्ट्रीय हाकी संघ ने इसे अपने कैलेंडर में ले लिया है। इसी कारण इस बार 'क्लासी फिकेशन' मैचों का भी आयोजन हुआ।

एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन खेल मंत्री लोकपति त्रिपाठी (वर्तमान स्वास्थ्यमंत्री) से वाराणसी में कहा था कि वह हाकी के लिए कुछ करें। इंदिरा गांधी की इस बात को साकार करने के लिए लोकपति त्रिपाठी जुट गये थे पर उस पर रंग चढ़ा इदिरा गांधी की मौत के बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी स्मारक स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता शुरू करने का कार्यक्रम तय हुआ। लोकपति त्रिपाठी चाहते थे कि यह प्रतियोगिता वाराणसी से शुरू हो, पर अंतरराष्ट्रीय हाकी संघ के इस फरमान ने कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता तभी मान्य होगी, जब वह सिन्थेटिक टर्फ पर होगी, लोकपति त्रिपाठी की इच्छा पर धूल डाल दिया। प्रतियोगिता तो होनी ही थी। इस प्रकार श्री गणेश हुआ दिल्ली से।

पर त्रिपाठीजी की शान तो तब होती, जब वह अपने प्रदेश में यंह तमाशा लगाते। समय की चुनौती बढ़ी—टर्फ आना और लगना अपने वश की बात तो थी नहीं, लेकिन जिस दिन बंबई से टर्फ खंडों में यहां आया, बात बनती लगी।

स्पोर्ट्स कालेज में एस्ट्रो टर्फ का लगना, ठीक घूरे के दिन लौटने वाली बात थी। एकाएक यह कालेज सुर्खियों में आ उठा, नहीं तो यहां की गतिविधियों से लोग बहुत अनजान थे।

प्रतियोगिता के दौरान देखें, तो हाकी का माहौल बनाने से कहीं ज्यादा लोगों से अपनी हैसियत बढ़ाने की होड़ रही। यही कारण रहा कि प्रतियोगिता के दौरान छोटी-बड़ी कई अशोभनीय घटनाएं हुईं।

प्रतियोगिता का दुरुपयोग: इस प्रति

योगिता को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसियेशन ने कराया, जबकि प्रदेश में हाकी की गतिविधियों के लिए उ०प्र० स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदार है, लेकिन उसे रायल्टी देकर दरकिनार कर दिया गया। रायल्टी के १५ हजार भी उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं और भविष्य में भी न मिलें, तो कोई अचरज वाली बात नहीं। पर एक बात साफ है कि प्रतियोगिता का आयोजकों ने दुरुपयोग किया। 'ध्यानचंद स्टेडियम' ३ करोड़ से ज्यादा की रकम पी गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ अधूरा है। इसके लिए अलग से पैसों की भी मांग उठ चुकी है। सूखे से कराहते इस प्रदेश में लोगों ने एक लाख की फुलवारी लगाने की भी जुर्रत दिखायी, ताकि माहौल महका-महका रहे, जबकि दूसरी तरफ 'बाबू खेल गांव' में शुरू में तो खिलाड़ी ठंड से सिकुड़ कर रह गये। उन्हें जो दो सिन्थेटिक रजाइयां मुहैया करायी गयी थीं, उनसे कहां सर्दी भागने वाली थी। यह बात जब लोकपति त्रिपाठी तक पहुंची, तो उन्होंने अतिरिक्त कंबल लाने का आदेश दिया।

संयोजन समिति ने यह दावा भी बड़े विश्वास के साथ किया कि वे प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ियों को इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। लेकिन इस शहर के ही दो ओलंपियन सैय्यद अली और रवींद्र पाल सिंह उनके लिए अनजान बन बैठे। सैय्यद अली ने मांट्रियल ओलंपिक (१९७६) और रवींद्र पाल सिंह ने दो ओलंपिकों (मास्को १९८० एवं लास एंजिल्स १९८४) में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उल्लेखनीय है कि मास्को में ही कई सालों बाद भारत का स्वर्ण-पदक जीतने का सपना पूरा हुआ था। क्या रवींद्र पाल एक निमंत्रण पत्र के भी हकदार नहीं थे? भारतीय हाकी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रवींद्र के साथ इस तरह का सलूक करने वाले क्या हाकी का भला कर सकेंगे? जब वह एक खिलाड़ी को पास नहीं दे सकते, तो फिर ये हाकी का माहौल क्या बनायेंगे?

बदइंतजामी :इन्हें तो पास ही नहीं मिले और जब मोहम्मद शाहिद जैसे खिलाड़ी अपने परिवार के साथ आये, तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। पद्मश्री पाने वाले मोहम्मद शाहिद को रोकने वाले क्या दंडित होंगे?

भले ही खेल खतम हो गये हैं, लेकिन राजनीति का खेल बंद नहीं हुआ है। अभी तो यही तय नहीं है कि इस एस्ट्रो टर्फ पर किसका अधिकार रहेगा। यह खेल निदेशालय के कब्जे में रहेगा या इस पर स्पोर्ट्स कालेज का अधिकार होगा। वैसे लोकपति ने यह कहकर कि स्टेडियम पर निदेशालय का कब्जा रहेगा, कालेज के अधिकारियों को सकते में डाल दिया है। वे कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनकी जमीन पर लगी चीज पर अधिकार किसी और का हो, फिलहाल कालेज के लोग मौन हैं। खेल निपट गया है, लेकिन टर्फ की रखवाली करना अब बड़ी चीज हो गयी है, यदि यह बेहाल पड़ा रहा, तो अगले साल का मेला, एक झमेला बन जायेगा।

—**प्रशांत शुक्ल**

पाकिस्तान को मिला चमचमाता इंदिरा स्वर्ण कप

पाकिस्तान ने द्वितीय इंदिरा गांधी स्मारक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता जीतकर यह साबित कर दिया है कि एशियाई हाकी का जवाब अब भी युरोप के पास नहीं है। जिस ढंग से पाकिस्तान ने छोटे-छोटे पासों के जरिये अपने 'मूव' बनाये, उसकी काट सोवियत टीम के पास नहीं थी।

एशियाई हाकी वह है, जो भारत और पाकिस्तान में खेली जाती है। मानो छोटे, छोटे पास, रिजर्व फ्लिक और डांज के जरिये लहराते हुए हमारे फारवर्ड जब चलते हैं, तो युरोपीय हाकी की धज्जियां उड़ जाना स्वाभाविक है। युरोपीय हाकी है हिट एंड रन। लेकिन पाकिस्तान ने जहां अपनी परंपरागत शैली से अपने लिए खुशियां बटोरी, वहीं भारतीय टीम ने युरोपीय शैली में खेलकर अपने लिये मुसीबत खड़ी कर ली। फल यह निकला कि ८ देशों के टूर्नामेंट में भारत पांचवा स्थान ही पा सका। मजे की बात तो यह है कि भारत ने यह स्थान भी तब पाया, जब उसने मैच में अपने ५ फारवर्डों को आजमाया, नहीं तो ३-३-३-१ की शैली से तो हम पर गोल ही गोल हो रहे थे। ५-३-२-१ की शैली हमारी अपनी शैली है, लेकिन नकल के चक्कर में हम बे-अक्ल होकर भटक रहे हैं।

भारतीय हाकी में जब से 'नकल' की प्रवृत्तिं जन्मी है, सफलता उससे कोसों दूर हो गयी है। इस टूर्नामेंट के नतीजे से तो भारतीय हाकी के मठाधीशों की आंखें खुल जानी चाहिए। प्रतियोगिता के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के स्वांस्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने भी यही कहा है कि अपनी परंपरागत हाकी खेलकर ही हम शिखर पर फिर से आ सकते हैं। युरोपीय शैली की नकल से हमारा भला होने से रहा।

९ दिन की प्रतियोगिता में ८ टीमें दो ग्रुपों में बंटकर खेलीं। भारत 'बी' ग्रुप में दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सोवियत संघ के साथ था, जबकि 'ए' ग्रुप में पाकिस्तान, कीनिया स्पेन, और न्यूजीलैंड थे।

'ए' ग्रुप में पाकिस्तान ने जहां अपने तीनों मैच जीतकर ६ अंकों से शिखर का स्थान पाया, वहीं मांट्रियल ओलम्पिक (१९७६) की स्वर्ण पदक विजेता न्यूजीलैंड की टीम ४ अंकों से द्वितीय रही।

ग्रुप 'बी' में सोवियत संघ शिखर पर और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रही।

सेमीफाइनल में ओलम्पिक चैंपियन पाकिस्तान ने एशियाई चैंपियन दक्षिण कोरिया को १-० से हराकर फाइनल खेलने का अधिकार पाया। दूसरे सेमीफाइनल में सोवियत संघ ने न्यूजीलैंड को आसानी से ३-० से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पाकिस्तान बनाम कोरियाई मैच में शुरू में तो कोरियाई टीम ने काफी गति दिखायी, लेकिन पूर्वार्द्ध की तरह उत्तरार्द्ध में वह फार्म नहीं रख पायी और शाहबाज ने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। शाहबाज को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया। फाइनल में भी उसने तीन गोलों में से एक गोल दागा था। पाकिस्तान के लिए अन्य गोल जाहिद शरीफ और कासिम खान ने किये। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को ३-२ से हराकर कांस्य पदक जीता।

विभिन्न टीमों की अंतिम स्थिति इस प्रकार रही:

१-पाकिस्तान २-सोवियत संघ ३-द० कोरिया ४-न्यूजीलैंड ५-भारत ६-मलेशिया ७-कीनिया ८-स्पेन

भारतीय टीम में लोगों ने मोहम्मद शाहिद व मेरविन फर्नांडीज की कमी बुरी तरह महसूस की। समझा जाता है कि इन्हें अब भारतीय टीम में ओलम्पिक के लिए शामिल कर लिया जायेगा। वैसे पांचवें स्थान पर आने के बावजूद भारतीय टीम के कप्तान एम०एम० सौमैया निराश नहीं हैं। उनका कहना है, "हमारा लक्ष्य तो ओलम्पिक है। हमारी टीम भी ओलम्पिक के लिए बन रही है।"

पाकिस्तान की जिस टीम ने यह स्वर्ण पदक जीता, उसके सदस्यों की औसत आयु महज १९ वर्ष है। इसमें तो ७ खिलाड़ी जूनियर हैं, लेकिन पाकिस्तान इस टीम को ही ओलम्पिक के लिए तैयार कर रहा है। हाकी के लिए जिस रंग-ढंग से तैयारी पाकिस्तान में चल रही है, उससे साफ है कि वे अपने ओलम्पिक खिताब की रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहां के 'ध्यानचंद स्टेडियम' में ही अब भारतीय टीम ओलम्पिक के लिए तैयारी करेगी। यहीं राष्ट्रीय हाकी होनी है; और अगले वर्ष एशिया कप हाकी भी यहीं होनी है। ■

राजनीतिक व आर्थिक विकेन्द्रीकरण ही एक मात्र रास्ता

– यशवंत सिन्हा, महासचिव जनता पार्टी

“भारत की सर्वप्रमुख और तात्कालिक समस्या है कि गरीबी का अभिशाप कैसे मिटाया जाये और जनता का जीवन स्तर कैसे उठाया जाये...यद्यपि गरीबी भारत में व्यापक पैमाने पर मौजूद है, किंतु यह मूलतः एक ग्रामीण समस्या है। इसकी खास वजह है, भूमि पर अत्यधिक दबाव और रोजगारों की कमी... ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच समुचित समन्वय और तालमेल से उद्योगों का विकास हो। अतीत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हुई और शहर गांवों की कीमत पर फलेफूले...योजना का लक्ष्य न केवल अधिकाधिक लोगों वरन शारीरिक रूप से सक्षम हरेक को रोजगार देने का होना चाहिए।”

उपर्युक्त उद्धरण किसी भी राजनीतिक दल के आज के घोषणापत्र के अंश हो सकते हैं। किंतु असल में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ११ दिसंबर, १९४५ के घोषणापत्र से लिये गये हैं। तब से गंगा में काफी पानी बह चुका है। ४० वर्षों से हम स्वतंत्र और अपनी नियति के निर्माता हैं। इन पूरे ४० वर्षों में मात्र तीन वर्षों को छोड़कर (१९७७ से १९८०) कांग्रेस दिल्ली में सत्तारूढ़ रही है। किंतु हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति से १९४५ की तुलना में काफी दूर हैं। इसके कारणों की गंभीरतापूर्वक जांच लाजिमी है।

हमारे स्वाधीनता सग्राम के दौरान दो समानांतर विचारधाराएं प्रमुख रूप से उजागर थीं। एक के प्रवर्तक थे, महात्मा गांधी और दूसरे के जवाहर लाल नेहरू। दोनों के सोच में भारी फर्क था। इन दो विचारधाराओं के बुनियादी दर्शन को लेकर स्वतंत्रतापूर्व जीवंत बहस छिड़ी रहती थी। स्वातंत्र्योत्तर काल में इनमें से एक विचारधारा सर्वशक्तिसंपन्न हो गयी, जबकि दूसरी उपेक्षित, तिरस्कृत और असहाय। चहेतों को प्रतिष्ठित करने के लिए ‘मंदिरों’ का निर्माण हुआ और दूसरों को उनके अकिंचन ‘आश्रमों’ से भी निर्वासित कर दिया गया।

नेहरू का आदर्श (माडल) बुरी तरह विफल हुआ है। लोग विकल्प के लिए अंधेरे में भटक रहे हैं। वे गांधीवादी विकल्प को देख पाने में अक्षम हैं, क्योंकि भारत की धरती से यह विलुप्त हो गया है। किंतु इसे पुनः मूर्तमान करके एक सशक्त आंदोलन चलाना देश के विभिन्न अभिशापों से मुक्ति के लिए परमावश्यक है। गांधीजी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ ही स्वाधीनता के संपूर्ण अर्थों की रूपरेखा भी विकसित की थी। भारत आने के पूर्व उन्होंने १९०९ में ‘हिंद स्वराज’ की रचना कर अपनी विचारधारा और भावी कार्यक्रमों को स्पष्ट किया था।

विकास की उनकी अवधारणा पश्चिमी पूंजीवादी माडल, जो लोगों की वासनाओं और इच्छाओं को भड़का कर फलताफूलता है, पर आधारित नहीं थी। वह व्यक्ति के भोगविलास को सीमित-संयमित रखने के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और तकनीक को खारिज करते हुए उसे गुलामी, गरीबी और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया।

“इसके सघन शहर, दैत्याकार कारखाने और विशाल शस्त्रागार घनिष्ठ रूप से इतने अंतरसंबंधित हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं,” गांधीजी ने जनवरी १९४० के ‘हरिजन’ में लिखा। किंतु वह उद्योगवाद के विरुद्ध थे, औद्योगीकरण के नहीं। एक पखवाड़े बाद उसी पत्र में उन्होंने लिखा, “मैं चाहता हूं कि भविष्य में ग्रामीण दस्तकारी के साथ-साथ बिजली, जहाज, लौह, मशीन आदि निर्माण के कार्य फूले-फलें। औद्योगीकरण की वर्तमान योजना गांवों व ग्रामीण दस्तकारियों को बर्बाद कर देगी। भविष्य में यह (औद्योगीकरण) गांवों और उनकी दस्तकारियों का विकास और संवर्धन करेगा।”...पुनः गांधीजी ने जनवरी १९३९ में लिखा, “शहरों में ऐसे किसी वस्तु के उत्पादन की इजाजत नहीं दी जायेगी, जिसे गांवों में भलीभांति तैयार किया जा सकता है। शहरों का काम ग्रामीण उत्पादों की खपत करना होगा।” इसकी तुलना आज के उच्च-तकनीक और सुपरकंप्यूटरों की क्षुधा-लिप्सा से करें।

वस्तुतः गांधीजी की भावी कल्पना का मूलाधार गांव थे। उनका यह बल किसी हठवादी का प्रलाप नहीं था। कारण तब भारत की बहुसंख्यक जनता (९० प्रतिशत) गांवों में रहती थी। अब भी ७६ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इस प्रकार गरीबी के खिलाफ जंग गांवों में लड़ी जानी चाहिए थी। गांधीजी को इस सच्चाई की जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने चर्खा-खादी व घरेलू उद्योगधंधों पर जोर दिया। इसीलिए वह शहरों द्वारा गांवों के शोषण के सर्वथा खिलाफ और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के पूर्ण समर्थक थे।

किंतु महात्मा गांधी के जीवन काल में ही उनके आदर्शों के समर्थक गिनती के लोग थे।

जवाहर लाल नेहरू जैसे उनके सर्वप्रिय शिष्य तक उनकी विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। नेहरू मानते थे, "गांव सामान्यतः बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं जो प्रगति के वाहक नहीं बन सकते।" उन्होंने गांधीजी के 'हिंदू स्वराज' के आदर्श को अस्वीकार कर १९२८ में ही कहा था, "पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता की भारत पर विजय अवश्यंभावी है।" उनकी यह भी टिप्पणी थी, मैं न तो यह मानता हूं कि तथाकथित रामराज्य अतीत के लिए बहुत अच्छा था, न मैं उसकी पुनः प्रतिष्ठा चाहता हूं।" उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि ही इस बात का फैसला करेंगे।

नेहरूवाद का बोलबाला : महात्मा गांधी की ३० जनवरी, १९४८ को हत्या कर दी गयी। जवाहर लाल नेहरू के हाथ में १७ वर्षों तक इस मुल्क की बागडोर रही। इसी प्रकार स्वाधीन भारत में नेहरूवाद की विजय हुई। गांधीवाद को रस्मी तौर पर राजघाट में दफना दिया गया।

भारत में लगभग ४० वर्षों तक नेहरूवाद के तहत छह पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल हुआ व सातवीं योजना जारी है। इस दौरान प्रगति हुई, किंतु ४० वर्षों में किस देश में प्रगति नहीं हुई? बहरहाल इस नजरिए की विफलताएं जगजाहिर हैं।

सरकार ने असंख्य बड़े उद्योगधंधे, बिजली, सिंचाई व परमाणु परियोजनाओं को लागू किया। हमने अंतरिक्ष में भी प्रवेश किया और आज हम सुपरकंप्यूटर पाने के लिए प्रयासरत हैं। किंतु व्यापक–विकराल गरीबी अभी भी मुंह बाये खड़ी है। हमारे गांव दरिद्रता, गंदगी और रोग के नर्ककुंड में सांस ले रहे हैं। अधिकांश गांवों में पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्न की भारी किल्लत है। शहरों का अधिकांश भाग भी झुग्गी-झोंपड़ियों से घिर गया है जहां नागरिक सुविधाएं नदारद हैं।

सरकार को अर्थतंत्र के संगठित क्षेत्र की अपनी जिम्मेदारियों का जहां अहसास रहा है, वहीं कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के प्रति वह दिग्भ्रमित बनी रही है। सरकार ने १९५० में ग्रामीण नीति प्रस्ताव तो अपना लिया, किंतु अभी तक कृषि नीति योजना से आंखें मूंदे हुए है। वह ग्रामीण विकास के लिए गांधीवाद की जगह पश्चिम का मुंह ताकती है। हमने बड़े धूमधाम से सामुदायिक विकास आंदोलन को देश में आरंभ किया। इसके तहत फौरी मसलों को हल करने की जगह हर गांव में गांधी चबूतरा और भजन मंडलियों के लिए ढोल-मजीरा मुहैया किया गया।

इस आंदोलन के बुरी तरह विफल होने के बाद कृषि, हस्तकला, घरेलू उद्योगधंधा, परिगणित व जनजाति विकास संबंधी अनेक योजनाएं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लागू की गयीं। किंतु इनका भी वही हश्र हुआ। लगभग १० वर्षों तक २० सूत्री कार्यक्रम-नये और पुराने-पर भी हाथ आजमाया गया।

इन सबसे ग्रामीण जनता तो नहीं, किंतु त्रिगुट-नौकरशाह, पंचायत प्रतिनिधि और ठेकेदार-अवश्य लाभान्वित हुआ। यही व्यवस्था का भरपूर दोहन कर रहे हैं और जनता जहां की तहां है। शोषकों का पेट और सरकारी आंकड़े पुस्तकों के पेट जरूर भर रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) में सैकड़ों करोड़ रुपए जरूर ऐंठे गये।

गांधीजी के लिए लोकतंत्र और पंचायत समानधर्मी थे। वह ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन, जिला प्रशासनों द्वारा प्रांतीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासनों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समर्थक थे। यही डा० लोहिया के 'चौखंभाराज' व रामकृष्ण हेगड़े के 'चार स्तरीय लोकतंत्र' का मूलाधार है। किंतु स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने इसकी पूर्ण उपेक्षा की थी। गांधीजी ने १ दिसंबर, १९४७ में हरिजन में लिखा था, "निःसंदेह संविधान सभा की कार्रवाइयां मेरी समझ से परे हैं...उसके दिशानिर्देश में ग्राम पंचायतों और विकेंद्रीकरण का उल्लेख नहीं है...।" काफी विरोध के बाद संविधान निदेशक सिद्धांत के अध्याय में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया।

इसके लिए संविधान की धारा ४० में की गयी व्यवस्था भी कागजी साबित हुई है। शक्तिशाली निहित स्वार्थों ने सुदृढ़ आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक निकायों की स्थापना में बाधाएं डालीं। गांधीवादी आदर्श और विचारधारा को त्यागने का नतीजा जगजाहिर है।

ये विचार आज भी प्रासंगिक होने के साथ-साथ राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। देश के सामने दरपेश विभाजनकारी प्रवृत्तियों का माकूल जवाब राजनीतिक व आर्थिक विकेन्द्रीकरण है। इसी से आर्थिक खुशहाली और ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनतम जनता के जीवनस्तर में गुणात्मक परिवर्तन संभव है। आज का सार्थक नारा है—गांधी की वापसी, गांवों की वापसी।

गांधीजी के लिए लोकतंत्र और पंचायत समानधर्मी थे। वह ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन, जिला प्रशासनों द्वारा प्रांतीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासनों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समर्थक थे। यही डा० लोहिया के 'चौखंभाराज' व रामकृष्ण हेगड़े के 'चार स्तरीय लोकतंत्र' का मूलाधार है। किंतु स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने इसकी पूर्ण उपेक्षा की थी। गांधीजी ने १ दिसंबर, १९४७ में हरिजन में लिखा था, "निःसंदेह संविधान सभा की कार्रवाइयां मेरी समझ से परे हैं... उसके दिशानिर्देश में ग्राम पंचायतों और विकेंद्रीकरण का उल्लेख नहीं है...।" काफी विरोध के बाद संविधान निदेशक सिद्धांत के अध्याय में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया।

तमिलनाडु में राजनीतिक संकट

क्या कांग्रेस जिम्मेदार है ?

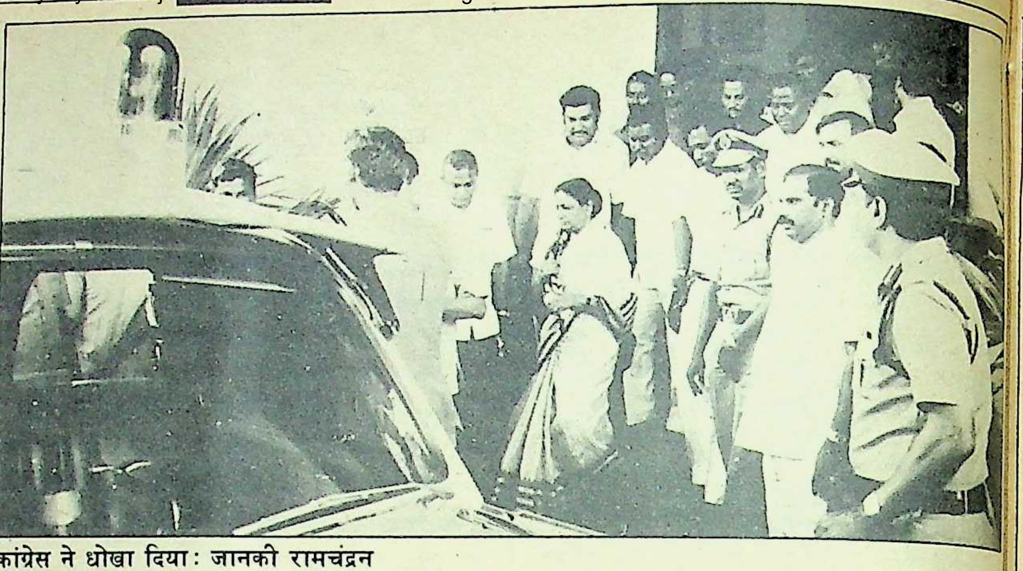

कांग्रेस ने धोखा दिया : जानकी रामचंद्रन

२८ जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा में जो कुछ हुआ, वह निश्चय ही चौकानेवाला और निंदनीय था। जहां बैठकर जन प्रतिनिधि लोकतंत्र कायम रखने के लिए कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित करते हों, अगर वहीं जूतमपैजार और हाथा-पाई होने लगे तथा दसियों के सिर टूट जायें, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ? सच तो यह है कि लोकतंत्र के नाम पर हम भले ही कितना गाल बजा लें, जड़ें हमारी अभी भी पूरी तरह खोखली हैं।

पूरे देश की नजर तमिलनाडु में हो रहे सत्ता-संघर्ष पर लगी थी। उम्मीद थी कि बहुमत परीक्षण के बाद प्रदेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता को विराम मिलेगा, मगर बहुमत-परीक्षण शक्ति-परीक्षण में तब्दील हो गया और इसके बाद जो कुछ हुआ, वह निहायत शर्मनाक और घटिया था। इस आपसी मारपीट का नतीजा यह निकला कि विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और जानकी रामचंद्रन केवल २३ दिन मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठकर किनारे लग गयीं।

घटना की शुरुआत पांच कांग्रेसी विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से हुई। शिवाजी गणेशन सहित पांच कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस द्वारा जानकी गुट को समर्थन न देने के विरोध में इस्तीफे दे दिये। क्रुद्ध कांग्रेसी विधायकों ने अध्यक्ष पी०एच० पांडियन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिये। इसी बीच इस्तीफा देने वाले विधायकों ने सभा में प्रवेश किया, तो दोनों खेमों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। जैसे-तैसे मामला शांत हुआ। अध्यक्ष ने दोपहर तक के लिए सदन स्थगित कर दिया और बहुमत-परीक्षण भी दूसरी बैठक के लिए टल गया। दूसरी बार जब सदन फिर शुरू हुआ, तो अध्यक्ष पांडियन ने जयललिता-गुट के छह पूर्व मंत्रियों की विधायकी खतम करने की घोषणा कर दी, जिससे एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इस बीच कुछ विधायकों ने पेपरवेट, माइक, कुरसी आदि फेंकना शुरू कर दिया।

इधर यह लड़ाई चल ही रही थी कि उधर कांग्रेस ने शिवरमन की 'अध्यक्षता' में समानांतर अधिवेशन शुरू कर दिया। इस अधिवेशन में वर्तमान अध्यक्ष को हटा दिया गया। जानकी-सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे भी बर्खास्त कर दिया गया और विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इन घटनाओं से मजबूर होकर विधानसभा दूसरी बार स्थगित करनी पडी।

दोपहर में तीन बजे सदन की बैठक फिर शुरू हुई। बैठक शुरू होती, इससे पहले ही दोनों विधानसभा अध्यक्षों पांडियन और शिवरमन के बीच कुरसी पर बैठने के लिए तू-तू, मैं-मैं होने लगी। इसके बाद विधानसभा लड़ाई के मैदान में बदल गयी। जिसके हाथ जो लगा, उसने अपने विरोधियों पर आजमाना शुरू कर दिया। खून-खराबे को देखकर पुलिस ने अंदर प्रवेश किया और लाठी चार्ज कर दिया, लिहाजा १७ इंकाई विधायक घायल हो गये और बहुतों को चोटें भी लगीं।

पुलिस प्रवेश के बाद कांग्रेस, जयललिता गुट, माकपा, भाकपा और द्रमुक के कुछ विधायक सदन से बाहर हो गये। इसके बाद बहुमत-परीक्षण हुआ। सदन में कुल ११० विधायक मौजूद थे। जानकी-गुट को उसके सभी ९९ विधायकों ने समर्थन दिया, जबकि उपस्थित आठ द्रमुक विधायकों ने विरोध में मत दिये। मुस्लिम लीग के भी दो विधायक उपस्थित थे, मगर उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। एक अन्य विधायक ने भी मतदान नहीं किया। इस तरह लगभग विपक्ष की अनुपस्थिति में जानकी-गुट ने बहुमत सिद्ध किया।

लेकिन श्रीमती जानकी की किस्मत में मुख्यमंत्री पद ज्यादा दिनों के लिए नहीं लिखा था। बहुमत-परीक्षण के ठीक दो दिन बाद यानी ३० जनवरी को विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी गयी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

हंगामे की वजह: यों एमजीआर की राजनीतिक विरासत की लड़ाई उनकी मृत्यु के बाद ही शुरू हो गयी थी। उनकी निरंकुश प्रवृत्ति के कारण मृत्यु के बाद अन्नाद्रमुक में नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया। इस तरह वर्षों से सत्ता में जमी अन्नाद्रमुक को दो धड़ों में बंटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक धड़े की बागडोर एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने संभाल रखी थी, तो दूसरे धड़े का नेतृत्व एमजीआर की करीबी मित्र जयललिता के हाथ थी। जानकी के पीछे वीरप्पन थे, तो जयललिता के पीछे नेदुनचेझियन। लेकिन इसके बावजूद इस अभूतपूर्व हंगामे की वजहें कुछ और थीं। राजनीतिक हलकों में इस सबके लिए प्रमुख रूप से दो कारण माने जा रहे हैं। एक-राज्यपाल की भूमिका और दूसरे कांग्रेस की भूमिका।

किसी भी राज्य में जब गैरइंकाई सरकार ढहती है और केंद्र में यदि इंका हो, तो राज्यपाल की कार्रवाई को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के कई अवसरों पर राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिह्न लग चुके हैं। आंध्र प्रदेश में जब राज्यपाल रामलाल ने रामराव की सरकार बर्खास्त कर दी थी, तो काफी बावेला मचा था। ३ जनवरी को जानकी-गुट के ९७ विधायकों से भेंट करने के बाद राज्यपाल एस०एल० खुराना ने श्रीमती जानकी को सरकार बनाने का अधिकार दे दिया, जबकि २३५ सदस्यों वाली विधानसभा में इससे कामचलाऊ बहुमत भी सिद्ध नहीं होता। फिर उन्होंने किस बिला पर सरकार बनाने का अधिकार जानकी गुट को दिया ? क्या उन्हें कांग्रेस द्वारा जानकी गुट को समर्थन देने संबंधी कोई आश्वासन मिला था ? यह कदम उठाने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति से सलाह-मशविरा किया था या नहीं ? एक प्रश्न यह भी है कि क्या उन्हें पता नहीं था कि श्रीमती जानकी को मुख्यमंत्री बना देने से उनका पलड़ा भारी हो जायेगा और यह जाने-अनजाने में हुआ एक पक्षपात ही कहा जायेगा, क्योंकि जानकी के मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता-धड़े के विधायकों का मन जानकी के साथ जाने को मचलने लगता। इसके अलावा विधायकों की खरीद-फरोख्त का माहौल बन जाता सो अलग। राज्यपाल खुराना द्वारा जानकी को समर्थन दिये जाने की एक वजह उनकी पत्नी की जानकी के साथ दोस्ती भी बतायी जाती है। कहा नहीं जा सकता कि इस बात में कितना दम है, मगर कुल मिलाकर

स्थिति राज्यपाल को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। बहरहाल और ज्यादा उंगलियां उठायी जातीं, इसके पहले ही राज्यपाल खुराना ने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी०सी० अलेक्जेंडर को नया राज्यपाल बनाया गया है।

कांग्रेस की भूमिका : बहुमत-परीक्षण के बाद जानकी रामचंद्रन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने ऐन वक्त पर उन्हें धोखा दिया। द्रमुक के अध्यक्ष करुणानिधि का भी कथन दिलचस्प था। उन्होंने कहा था कि जो मेढक सांप की शरण में जाता है, उसका यही हश्र होता है। लेकिन क्या कांग्रेस ने सचमुच जानकी को धोखा दिया? क्या बहुमत-परीक्षण में उसने जानकी को समर्थन देने का भरोसा दिया था?

दरअसल इस पूरी उठा-पटक में कांग्रेस की भूमिका के कई पहलू हैं। ७ जनवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जानकी रामचंद्रन दिल्ली दरबार में राजीव का समर्थन प्राप्त करने गयी थीं। बाद में उनके बयानों से कहीं भी साफ तौर पर यह संकेत नहीं मिला कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था या नहीं। हां, इस मुद्दे पर वह विचार करेगा, ऐसा संकेत जरूर मिला था। शायद इसी आश्वासन पर जानकी ने भरोसा कर लिया हो, जो आखिरी समय में उनके लिए घातक सिद्ध हुआ।

तमिलनाडु कांग्रेस-इ का अंतर्कलह भी इसके लिए काफी कुछ जिम्मेदार है। पार्टी में एक गुट, जिसका नेतृत्व शिवाजी गणेशन कर रहे थे, जानकी का समर्थन करना चाहता था, जबकि दूसरा गुट खिलाफत। यह तो जगजाहिर है कि कांग्रेस का रुख हमेशा जयललिता के प्रति नरम रहा है और तमिलनाडु की राजनीति में उसके लिए वह महत्वपूर्ण मोहरा हैं। अत: जानकी के समर्थन का मतलब था जयललिता से हाथ धोना और वह ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगी। जानकी-धड़े की मुख्य बागडोर आर०एम० वीरप्पन के हाथ में है, यह उसे बखूबी पता है। वीरप्पन श्रीलंका-समझौते की खिलाफत करते रहे हैं और कांग्रेस के कट्टर विरोधी भी हैं। जाहिर है, जानकी को समर्थन देने का मतलब वीरप्पन की हैसियत बढ़ाना है और इसका मतलब होगा, श्रीलंका-समझौते की जड़ें खोदना। हालांकि मुख्यमंत्री बनते ही जानकी ने समझौते का समर्थन करने की घोषणा कर दी थी, मगर एक बार बहुमत सिद्ध करने के बाद वीरप्पन हावी हो जाते, जोकि कांग्रेस के लिए कतई अच्छा नहीं होता।

जानकी और राजीव गांधी के दिल्ली मिलन के बाद जयललिता-गुट में यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि कांग्रेस जानकी सरकार का समर्थन न कर दे। जानकी सरकार को ध्वस्त करने के लिए कमर कस चुकी जयललिता ने पैंतरा बदला। जानकी से राजीव के मिलन के बाद जयललिता ने कई कोशिशें कीं, राजीव गांधी से मिलने की, पर सफलता नहीं मिली।

बताया जाता है कि २८ जनवरी के एक दिन पहले जयललिता की मुलाकात राजीव गांधी से हुई। सूत्रों का कहना है कि उसी दिन कांग्रेस की रणनीति तय हो गयी थी कि २८ जनवरी को कांग्रेसी विधायक जानकी का समर्थन नहीं करेंगे।

कांग्रेस की भूमिका में जी०के० मूपनार और केंद्रीय मंत्री पी० चिदंबरम भी शामिल हैं। कहा जाता है कि जानकी-सरकार के गिरने में मूपनार की खासी दिलचस्पी थी और वह यह कतई नहीं चाहते थे कि कांग्रेस उसका समर्थन करे। अत: इसके लिए उन्होंने पार्टी में लाबी मजबूत कर ली थी। इसी तरह पी० चिदंबरम भी पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत थे। इस तरह पार्टी साफ तौर पर तीन धड़ों में बंट गयी थी।

लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र ने चुपचाप मजा लेना तय कर रखा था। इसलिए अंत तक उसने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि वह जानकी सरकार को समर्थन देगी या नहीं? और सारे हंगामे की वज़ह भी यही बनी।

इस घटनाचक्र में राष्ट्रपति वेंकटरमन का नाम भी जोरों से उछला। कहा जाता है कि वह जानकी सरकार को बनाये रखने के पक्ष में थे। हाल के वर्षों में राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति का पद भी राजनीतिक हो गया है। यह अत्यंत निराशाजनक है। बाद में राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति जारी की गयी, जिसमें उक्त आरोप का खंडन किया गया है।

भावी राजनीति: तमिलनाडु की भावी राजनीति क्या मोड़ लेगी, यह कहना अभी मुश्किल है। काफी कुछ तो इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव कब होते हैं। केंद्र सरकार जल्द-से-जल्द चुनाव कराने की इच्छुक जान पड़ती है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि वह रामचंद्रन की मृत्यु से उपजी सहानुभूति को भुनाना चाहेगी। यद्यपि इसका सीधा लाभ तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जयललिता-धड़ा इस लहर का फायदा उठा सकता है और उसने जयललिता को हमेशा अपना समर्थन दिया है। मौजूदा परिस्थितियों में एमजीआर की मृत्यु से उपजी सहानुभूति का फायदा जानकी की बनिस्पत जयललिता को मिलने की अधिक संभावना है। चूंकि कांग्रेस द्वारा खुद सरकार बनाने की सभावना नहीं के बराबर है, इसलिए वह अपने मन की सरकार यानी जयललिता की सरकार बनाने की ही कोशिश करेगी। इस लिहाज से जयललिता का पलड़ा भारी नजर आता है। कांग्रेस द्वारा जल्दी चुनाव कराने का दूसरा कारण है, अपनी पार्टी के अंदर पनप रही फूट को दबाना। शिवाजी गणेशन के साथ अभी चार ही विधायक गये हैं। कांग्रेस के लिए यह अच्छी बात है कि इसके बाद और किसी का इस्तीफा नहीं आया है, मगर देर करने से बदलते हवा के रुख के अनुसार अन्य कांग्रेसी विधायक भी इरादा बना सकते हैं। शिवाजी गणेशन का प्रभाव पार्टी में भले ही बहुत न रहा हो, मगर पार्टी के अन्य प्रादेशिक नेताओं के मुकाबले उनकी हैसियत कम नहीं है। वह भी फिल्म इंडस्ट्री की देन हैं और तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी चरित्र हमेशा हावी रहे हैं।

मौजूदा परिस्थितियों में एमजीआर की मृत्यु से उपजी सहानुभूति का फायदा जानकी की बनिस्पत जयललिता को मिलने की अधिक संभावना है। चूंकि कांग्रेस द्वारा खुद सरकार बनाने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए वह अपने मन की सरकार यानी जयललिता की सरकार बनाने की ही कोशिश करेगी।

हाल में तमिलनाडु के एक अखबार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रदेश में इस समय सबसे लोकप्रिय नेता करुणानिधि हैं। हालांकि श्रीलंका-समझौते के खिलाफ चलाये गये आंदोलन में उन्हें तमिल-जनता का समर्थन बहुत ज्यादा नहीं मिला था, मगर अन्नाद्रमुक के दो फाड़ का फायदा उन्हें मिल सकता है। विधानसभा में उसके २२ विधायक थे, जिसमें से १० की सदस्यता बाद में समाप्त कर दी गयी थी। इस सबके बावजूद उनके पक्ष में कई बातें जाती हैं। पहली तो यही कि यदि तमिल जनता तमिल मुख्यमंत्री ही चाहे, तो जानकी और जयललिता दोनों की दावेदारी रद्द हो जानी है। जानकी रामचंद्रन केरल की हैं और जयललिता कर्नाटक की। दूसरा कारण भी इसी तरह का है। तमिल जनता शायद ही यह पसंद करे कि उत्तर उन पर शासन करे। इसका मतलब होगा कांग्रेस और जयललिता दोनों को नकार देना। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस का जो रवैया हाल में रहा है, उसने इस बात को और हवा दी होगी। और फिर चुनाव में यही सब मुद्दे तो भुनाये जाते हैं। करुणानिधि ने हिंदी विरोधी आंदोलन के जरिये भी खासी लोकप्रियता अर्जित की थी। यह और बात है कि करुणानिधि की ज्यादातर नीतियों को अलगाववादी कहा गया है, मगर यही वे वजहें भी हैं, जिनसे वह तमिलों के करीब पहुंचे।

इस स्थिति में जानकी गुट को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि जानकी रामचंद्रन कोई मंजी हुई राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह राजनीतिज्ञ हैं ही नहीं, लेकिन उनके पीछे वीरप्पन जैसे घाघ राजनीतिज्ञ का दिमाग है। वीरप्पन अनुभवी और चालाक नेता हैं। खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की बजाय जानकी को आगे करके उन्होंने यह साबित भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा ९९ विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। जानकी का उनके साथ होना भी उनके लिए फायदेमंद है, भले ही राजनीति के क्षेत्र में अनाड़ी ही क्यों न हों। इसके अलावा कई मामलों में वह करुणानिधि के करीब हैं। यदि द्रमुक और उनके गुट में कुछ समझौता हो गया, तो सारे समीकरण पल भर में उलट सकते हैं। जानकी गुट द्वारा श्रीलंका समझौते के विरोध करने की घोषणा से भी यही साबित होता है। **—मुकेश कुमार**

एयर टैक्सियां

दलाली के नये स्रोत

TRANS-CANADA AIR LINES

एयर टैक्सियों की योजना किसके दिमाग की उपज है? क्या हमारे देश के लिए इनकी कोई उपयोगिता है?

क्या हमें ऐसे विमान चाहिए: एयर कनाडा का एक विमान

भारत के लिए यह प्रयोग नया नहीं है। १९५३ के पूर्व देश की घरेलू उड़ानों में अनेक निजी विमान सेवाएं थीं। इनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ही सरकार ने भारी सबसीडी देकर इनका राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एअर लाइंस की नींव डाली थी। आखिर ४० वर्ष से कम की अवधि में हमें यह पुराना असफल प्रयोग दोहराने की क्या जरूरत पड़ गयी? कहीं यह योजना आर्थिक अपराधों को लेकर पिछले दिनों उछलने वाले सत्ता के गलियारों से जुड़े चंद लोगों के लाभ के लिए तो नहीं है? या यह योजना हवाबाजी से राजनीति में आये प्रधानमंत्री और उनके हवाबाज सलाहकारों का तुगलकी खयाल है?

दरअसल एअर टैक्सी चलाने की यह योजना विनियंत्रीकरण के अमरीकी प्रयोग का भारतीय संस्करण है। किन्तु पर्यटन को बढ़ावा देकर और विदेशी मुद्रा कमाकर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के खयाली पुलाव पकाने वाले हमारे कर्णधारों को यह बात सोचनी होगी कि जहां व्यावसायिक दक्षता के बावजूद यह योजना अमरीका में असफल हुई है, वहां मौजूदा हालात में लाभ में चल रहे भारतीय परिवहन तंत्र की घरेलू उड़ानों को इस असफल योजना के अनुकरण की क्या जरूरत है? वायु परिवहन क्षेत्र में अमरीका ने बढ़ते हुए यात्री दबाव, घटती तेल कीमतों और गिरते श्रममूल्यों के बीच स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और विमान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए १९७६ में वायु परिवहन का विनियंत्रीकरण किया था। विनियंत्रीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण (आई०ए०टी०ए०) ने १९८४ में इस प्रयोग से अमरीकी घरेलू उड़ानों पर पड़े प्रभावों की परीक्षा के लिए 'विनियंत्रीकरण जांच समिति' का गठन किया। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि अमरीकी प्रयोगों के अध्ययन से अन्य देशों के वायु परिवहन को भी पर्याप्त लाभ मिल सके। यह वही समय था, जब भारत को २१वीं सदी में ले जाने की परिकल्पना के चलते अमरीका के ठीक बराबर सोच के परिणामस्वरूप विनियंत्रीकरण की दिशा में ही हमारे यहां वायु टैक्सियां चलाने की योजना पर अमल की कोशिशें की जा रही थीं। लगभग ३ वर्षों के सागर मंथन के बाद अब जल्दी ही इस योजना को लागू किया जाने वाला है। मगर छब्बे बनने के चक्कर में यह प्रयोग दोहरा कर चौबेजी दूबे हों, इसके पहले अमरीकी विनियंत्रीकरण अध्ययन समिति की चौथी रिपोर्ट की कुछ जानकारियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

असफल प्रयोग: इस रिपोर्ट के मुताबिक विनियंत्रीकरण ने वायु परिवहन व्यवसाय में आर्थिक अनिश्चिंतता पैदा की है। कार्यात्मक अनुपात (व्यवसाय में लगी पूंजी और खर्च के बीच का संबंध) के आर्थिक पैमाने पर किसी भी वर्ष इसका अनुपात इतना नहीं था कि लंबे समय के लिए ज्यादा धन लगाकर लाभ की सम्भावना से आश्वस्त रहा जा सके। उदाहरण के लिए वर्ष १९८६ में यह अनुपात १०१.९२ था। पूरे उद्योग को इस वर्ष २२.७ करोड़ अमरीकी डालर का शुद्ध घाटा हुआ। खासकर 'पान अमेरिकन' जैसी महत्वपूर्ण इकाई का घाटा ८८.३ प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कार्यात्मक अनुपात से यह पता चलता है कि उद्योग के पास पूंजी वितरण के लिए कितना अपेक्षित धन उपलब्ध है, जिसे भविष्य में इस व्यवसाय में लगाया जा सकेगा। मगर इस प्रयोग के बाद अनेक एअरलाइने भारी कर्जदार हो गयीं, क्योंकि आर्थिक असफलता के दौर में उनके पास कर्ज लेना ही पूंजी प्राप्ति का एकमात्र बड़ा जरिया था, जबकि एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइंस अपने विस्तार के साथ-साथ समय-समय पर अपनी लाभकारी स्थिति बनाये रखने के लिए सरकार से सहज ही किराया बढ़ाने की अनुमति प्राप्त कर लेती है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में स्थिति इसके विपरीत होगी। तब आज की हमारी घरेलू उड़ानों की लाभकारी स्थिति बनाये रखना कठिन होगा।

'मूल्य प्रतिद्वंद्विता' अमरीकी एअरलाइनों की असंतोषजनक आर्थिक स्थिति की एक बड़ी वजह है। इसके कारण उनकी आमदनी काफी घट गयी। इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के चलते टिकटों में दी जाने वाली छूट के कारण १९८६ की औसत आमदनी में ८ प्रतिशत की कमी आयी। हालांकि इस दौरान अमरीका में श्रम और ईंधन दोनों के मूल्यों में कमी से एअर लाइनों को राहत भी मिली है। भारत में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। जब विश्व बाजार में

In its 64-seat configuration, ATP has an average break-even load of 21 passengers
BRITISH AEROSPACE
ATP

दलालों की चांदी : ब्रिटिश एयरो स्पेस का यात्री विमान

तेल के दामों में कमी हुई थी, तब भी भारत में तेल की खपत पर अंकुश लगाने के लिए उस पर कर बढ़ा दिया गया था। यह कर कम करने या किराया बढ़ाने के लिए इंडियन एअर लाइंस ने पहले ही सरकार से अनुरोध किया है। दूसरी ओर ईंधन और श्रम मूल्यों में कमी के साथ-साथ अति उत्तम प्रबंध व्यवस्था वाली अमरीकी इकाइयों की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल अमरीका की मौजूदा विनियंत्रित व्यवस्था में आर्थिक अनिश्चिंतता एक स्थायी भाव सा हो गया है।

ऐसी स्थिति में आर्थिक केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिला। फलतः टेक्साज एअर कार्पोरेशन, अमरीका की सबसे बड़ी वायु परिवहन इकाई बन गयी। हाल के वर्षों में केवल प्रथम श्रेणी की उड़ान सेवा प्रदान करने वाली एक इकाई के अलावा अमरीका में कोई अन्य इकाई अस्तित्व में नहीं रही। इन इकाइयों की असफलता के अनेक उदाहरण सामने आये हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय मामला 'पीपुल्स एक्सप्रेस' का है। इतना ही नहीं 'वर्ल्ड-एअर' और 'ट्रांस अमेरिका' जैसी छोटी इकाइयां भी बंद हो गयीं। इस गलाकाट प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप १९८७ तक पहुंचते-पहुंचते अमरीका की २२ मुख्य राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की संख्या घटकर १४ रह गयी।

असफलता के कारण : भारत में निजी वायु सेवा के राष्ट्रीयकरण के तीन दशक बाद शुरू की गयी 'वायुदूत' सेवा की घरेलू उड़ानों में मिली व्यावसायिक सफलता की कहानी के ठीक विपरीत अमरीका में 'पीपुल्स एक्सप्रेस' की असफलता और 'टेक्साज एअर' द्वारा उसके अधिग्रहण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। 'पीपुल्स एक्सप्रेस' की आरंभिक प्रचण्ड सफलता पर यह कहा जाता था कि उसने स्थापित औद्योगिक तंत्र को तोड़ डाला है, लेकिन यह आशा बांझ निकली। इसकी असफलता के ये तीन प्रमुख कारण हैं—जो भारतीय संदर्भों में भी बेहद महत्वपूर्ण हैं :

१. लम्बी उड़ान वाली एअर बसों का न सिर्फ विचलित होकर छोटी उड़ानों में बदलना बन्द हो गया, वरन् इसकी संभावना संतुष्टि के बिन्दु पर पहुच गयी, जबकि उनकी क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है।

२. उच्च श्रेणी की उड़ानों पर जोर देने की विवशता आ गयी, लेकिन इन इकाइयों की छवि इसके विपरीत थी और अपनी नयी भूमिका में वे बड़ी इकाइयों से सीधे टकरा गयीं।

३. छोटी इकाइयों का अपेक्षाकृत अल्पविकसित प्रबंध तंत्र इतने व्यापक और द्रुतगामी विस्तार की व्यवस्था करने में अक्षम था। इससे हर स्तर पर टूट-फूट, भूल-चूक और गलतियां होने लगीं।

इस स्थिति में यह संभव था कि ये इकाइयां किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमातीं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें दूसरा क्षेत्र चुनने को मजबूर होना पड़ा और यहीं वे मार खा गंयीं। अमरीका की मौजूदा स्थिति में इन इकाइयों को अपना आकार बढ़ाना एक विवशता है। वायु परिवहन की फैशनेबुल भाषा में कहें, तो इन इकाइयों को जीवित रहने के लिए एक क्रांतिक गुरुत्व (क्रिटिकल ग्रेविटी) प्राप्त करना ही है। दिलचस्प बात यह है कि यह रोग बड़ी इकाइयों को भी लग गया है और बाजार में एक प्रतिशत अधिक हिस्सेदारी के लिए वे लगभग ३० करोड़ डालर देकर छोटी इकाइयों का अपने में विलय कर रही हैं। 'अमेरिकन एअर लाइंस' में 'एअर काल' का विलय इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि अमेरिकन एअरलाइंस ने दावा किया है कि वह अभी भी विलय और अधिग्रहण को नहीं, बल्कि विस्तार को अपने व्यवसाय की रणनीति मानती है। इससे तो यही लगता है कि क्रांतिक गुरुत्व का अर्थ लगातार अपने वजन से ज्यादा वजन बढ़ाते रहना ही हो गया है।

अमरीका में पनपी इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि जहां १९८५ में ५ प्रमुख उड़ान इकाइयों ने कुल यात्री मील में ६९.३ प्रतिशत हिस्सा पाया था, वहीं १९८६ में यह प्रतिशत बढ़कर ७६.७ हो गया। दूसरी ओर वहां की ९ मुख्य इकाइयां समस्त घरेलू यात्री मील का ९४ प्रतिशत हिस्सा हथियाये हुए हैं। बढ़ती हुई इस आपाधापी के चलते अमरीका की बड़ी इकाइयों ने छोटे-छोटे केन्द्रों (हब्ज मार्केट) पर भी प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी यात्रा संरचना में इन केन्द्रों (हब्ज) की संख्या का काफी प्रतियोगितात्मक महत्व था। और प्रत्येक केन्द्र पर

यातायात के नियंत्रण में उनकी सहभागिता का अनुपात भी काफी महत्वपूर्ण होता है।

चालकों का अभाव: भारतीय संदर्भ में इस प्रयोग की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशिक्षित चालकों व अन्य प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत पड़ेगी। भारतीय परिवहन तंत्र में यह कमी पहले से ही है। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र से लगे फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी की प्रशिक्षित पायलटों की पहली खेप आने के बावजूद यह कमी पूरी नहीं होती। ऐसी हालत में क्या वायु टैक्सियां अप्रशिक्षित और अकुशल चालक चलायेंगे? या इसके लिए नये-पुराने विमानों की खरीद के साथ पायलट भी विदेशों से बुलाये जायेंगे?

विनियंत्रीकरण के बाद अमरीका की बड़ी इकाइयां इन केन्द्रों (हब्ज) के अलावा छोटी. विमान (फीडर) सेवाओं में अपना वर्चस्व ही कायम करना नहीं, उन्हें हथियाना भी चाहती हैं। अभी तक ये बड़ी इकाइयां छोटी विमान सेवाओं से तमाम किस्म के समझौते करके अपना काम करती थीं, लेकिन अब वे उनका अधिग्रहण कर रही हैं। हालांकि उस स्थिति में उन्हें उस छोटी विमान कम्पनी की एक निश्चित स्तर की सुरक्षा और सेवा की गारंटी लेनी पड़ती है। इससे बचने के लिए व्यवसायियों. ने 'कोड शेयरिंग' नामक नायाब तरीका निकाला है। .इसमें बड़ी इकाइयां छोटी विमान कंपनियों को अपना उड़ान चिन्ह प्रदान करती हैं। फलतः बड़ी विमान सेवाओं से जुड़ने वाली छोटी विमान सेवाओं की उड़ानों को अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय आरक्षण सूची में स्थान मिल जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह सीधी उड़ान हो। सच तो यह है कि इससे यात्रियों में यह भ्रम पैदा किया जाता है कि वह उस बड़ी इकाई की सेवा ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह यात्रियों को धोखा देने का तकनीकी तरीका है। जबरदस्त होड़ के चलते इस व्यवस्था ने ऐसे तमाम तरीके ईजाद कर दिये जो यात्रियों अथवा प्रशासन को फरेब देकर एअरलाइनों के लिए लाभ का कारण बनाते हैं।

एजेंटों की चांदी: एअरलाइनों की इन्हीं विवशताओं के चलते विनियंत्रीकरण के बाद ट्रेवेल एजेंट बेताज बादशाह हो गये। १९७८ से १९८६ की अवधि में इनके कमीशन में १४३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इस बीच प्रति यात्री मील राजस्व की कुल लागत में केवल ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई। इनकी बादशाहत की बदौलत ही इन्हें १९७८ में मिलने वाला ८.३ प्रतिशत कमीशन १९८६ में बढ़कर १० प्रतिशत हो गया। इन्हें दोहरे लाभ मिले। एक ओर उडान इकाइयों द्वारा व्यावसायिक कारणों से इन्हें अधिक महत्व मिला। दूसरी ओर वायु परिवहन की तमाम जटिलताओं की वजह से यात्रियों को ऐसा एहसास होता है कि ट्रेवेल एजेंट ही उनकी सुविधाजनक और कम खर्चीली यात्रा की व्यवस्था कर सकता है। फलतः अमरीका में १९७८ की १६६२८ ट्रेवेल इकाइयों की संख्या १९८६ में बढ़कर २८७९४ हो गयी अर्थात ७ प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि। वायु कंपनियों की तुलना में [illegible] कंपनियां असफल भी बहुत कम हुईं। वर्ष १९८६ में असफल इकाइयों की संख्या ४०३ थी जो कुल इकाइयों का १.४ प्रतिशत है। अच्छी बात यह है कि टिकट बिक्री की व्यवस्था में छोटी इकाइयों का प्रभुत्व बना हुआ है। १९८५ में ४ करोड़ डालर के वार्षिक टिकट बेचनेवाली बड़ी कंपनियों का एजेंसी द्वारा वितरित टिकट में मात्र ०.२ प्रतिशत हिस्सा था, जबकि ५० लाख डालर वार्षिक टिकट बेचने वाली छोटी विमान कंपनियां, इसमें से ९९.५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर रही थीं।

विकेंद्रीकरण के प्रयोग ने आधारभूत व्यवस्था और हवाई अड्डे में उपलब्ध स्थान पर बहुत अधिक दबाव डाला है, जबकि इंडियन एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के बाद घरेलू उड़ानों में प्रतिदिन १२०० यात्री ढोने की क्षमता आज बढ़कर २८००० यात्री प्रतिदिन तक पहुंच गयी है। इस कारण भारतीय हवाई अड्डों पर पहले ही बेहद दबाव है। अभी हम अपने यहां के प्रमुख हवाई अड्डों पर आटो लैंडिंग व नाइट लैंडिंग सुविधाएं ही पूरी तरह उपलब्ध नहीं करा सके हैं। खास बात यह है कि विनियंत्रीकरण की विचारधारा की वजह से इस दबाव को कम करने के लिए जरूरी उपाय भी नहीं किये जा सकेंगे। फिर इसके बाद हमारे हवाई अड्डों की स्थिति क्या होगी?

इस व्यवस्था में हवाई अड्डों पर उपलब्ध स्थान पर दो तरह से प्रभाव डाला है:

१. छोटे केंद्रों की उड़ानों के बढ़ते महत्व के कारण मुख्य हवाई अड्डों पर काफी भीड़ बढ़ गयी है।

२. विमान कंपनियों के लिए अपने विमान की यात्री क्षमता बढ़ाने की अपेक्षा उडान सेवा की अवधि बढ़ाना अधिक लाभदायक होता है। इससे हवाई अड्डो पर उड़ानों का दबाव बढ़ गया है।

पिछले ५ वर्षों में उड़ान सेवाओं के विमानों की औसत क्षमता बराबर १५५ पर टिकी हुई है, जबकि इस बीच हवाई यातायात में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। 'विनियंत्रीकरण जांच समिति' की चौंकाने वाली रिपोर्ट के परिणाम इस बात का संकेत है कि एअर टैक्सी योजनाओं को लागू करते समय भारतीय नीति निदेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि प्रतिस्पर्धा जहां एक और असफल विमान कंपनियों को घाटे में लायेगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालेगी इंडियन एअर लाइंस के प्रबंधक पहले ही बढ़ती हुई तेल कीमतों व अन्य कारणों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से किराया बढ़ाने की अनुमति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

पिछले ५ वर्षों में उड़ान सेवाओं के विमानों की औसत क्षमता बराबर १५५ पर टिकी हुई है, जबकि इस बीच हवाई यातायात में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। विनियंत्रीकरण जांच समिति की चौंकाने वाली रिपोर्ट के परिणाम इस बात का संकेत हैं कि एअर टैक्सी योजनाओं को लागू करते समय भारतीय नीति निदेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि प्रतिस्पर्धा जहां एक और असफल विमान कंपनियों को घाटे में लायेगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालेगी।

अमरीकी संदर्भ के ठीक विपरीत भारत में मुख्य विमान सेवाएं, चाहे वह एअर इंडिया हो या इंडियन एअर लाइंस, वायुदूत अथवा पवनहंस हो केवल सरकारी क्षेत्र में हैं। जिसका अर्थ यह होगा कि प्रयोग की असफलता पर सरकार को बीमार मिलों उद्योगों आदि की तरह ऐसी असफल विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय मुख्य विमान सेवाओं में मिलाना पडेगा।

उस स्थिति में विभिन्न तरह के समान यात्री क्षमता वाले जहाज, इकट्ठे होकर एअर लाइंस के देखरेख (मेण्टीनेंस) और परिचालन खर्चों को बढ़ायेंगे, जिसका अप्रत्यक्ष भार भारतीय जनता पर पड़ेगा। पवन हंस के लिए खरीदा गया वेस्ट लैंण्ड हेलीकाप्टर इसका एक उदाहरण है। प्राइवेट कंपनियों के इस क्षेत्र में आने के साथ ही एअर टैक्सियों के रूप में नये-पुराने विमान खरीदे जायेंगे। कोई ताज्जुब नहीं, असफल अमरीकी विमान कंपनियों के हैंगर में खड़े विमान एअर टैक्सी की उड़ान में शामिल हो जायें? बंबई स्थित पुराने जहाज बेचने का बेताज बादशाह जो कोजारिक इस योजना के चलते पुराने अमरीकी विमान भारत के मत्थे मढ़कर कुछ और अमीर हो जाये, तो आश्चर्य नहीं।

यह भी तय है कि पुराने विमानों की खरीद-फरोख्त के साथ व्यवसायियों को आर्थिक लाभ की दृष्टि से अण्डर-ओवर इन्वायसिंग करके विदेशी मुद्रा कमाने का एक और सहज रास्ता मिल जायेगा। साथ ही भारत की प्रमुख विमान सेवाओं द्वारा नये क्षेत्रों में बढ़ायी गयी लाभकारी सेवाओं की आमदनी पर भी यह प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिससे इनकी स्थिति भी खराब हो सकती है। वैसे भी लाभकारी मार्गों के विकास का खर्च तो सरकारी उड़ानों के सिर रहेगा। जब उनसे फायदा उठाने की स्थिति होगी तब यज्ञ के देवताओं की तरह वायु टैक्सियों के मालिक मुफ्त में यज्ञ की हविश खाने के हकदार हो जायेंगे। उल्लेखनीय है १९५३ तक हमारी घरेलू उड़ानों में लगभग ४६ विमान सेवाएं चल रही थीं। इनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण सरकार ने भारी सबसीडी देकर अंततः इनका राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एअर लाइंस बनायी। भारत जैसे सीमित साधनों वाले देश में आवश्यकता धन स्रोतों का भलीभांति उपयोग करने की है, न कि उन सीमित साधनों पर दबाव डालकर मंहगे व असफल प्रयोगों को दोहराने की जिनके कड़वे अनुभव हमारे इतिहास का हिस्सा हों।

—दिलीप कुमार

अब केवल देखने के लिए ?

Colgate
Signal
Cibaca Top
Jai
Rin
Lux

क्या आम लोग इनका उपयोग कर सकेंगे ?

नया बजट

और कर लगेंगे

आने वाले बजट में क्या कुछ होगा, इसका असली पता तो बजट आने पर ही चल सकेगा, लेकिन 'माया' के अर्थ विशेषज्ञ के पूर्वानुमान से जो तस्वीर उभरती है, उससे रोजमर्रा की वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं।

आने वाले बजट की तीखी मार लगभग हरेक पर पड़ेगी। तकबरीन हरेक परिवार की वास्तविक आय में कमी आयेगी। इसके कारण हैं। एक तो अधिक कर लगेंगे। इसके दो तरीके होंगे। आयकर दाताओं को और ज्यादा कर देना होगा और जो वेतन वे घर ले जायेंगे, वह पहले से कम होगा। मुमकिन है, ऐसा सबके साथ न हो, किंतु जिन लोगों की मासिक आय ६ हजार रुपए या उससे अधिक है, वे जरूर प्रभावित होंगे। उपभोक्ता सामान तैयार करने वाले को कच्चे माल पर कर की दर ऊंची होने के कारण उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी तथा खरीदार को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

इसके अलावा आम मुद्रास्फीति होगी, जिसका अर्थ होगा अधिकांश जिंसों की मूल्यवृद्धि। मुद्रास्फीति उन वस्तुओं को भी महंगा कर देती है, जिन्हें किसी अतिरिक्त कर का बोझ सहना नहीं पड़ता। मूल्यों पर ऐसी संपूर्ण बढ़ोतरी का किस रफ्तार से असर पड़ेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है, किंतु निस्संदेह इसकी गति बहुत तीव्र होगी। इसकी एक अहम वजह 'घाटे की अर्थव्यवस्था' के नाम से जानी जाती है। सीधे-सादे शब्दों में इसका मतलब है कि सरकार अधिक नोट छापती है और उतनी तादाद में धन खर्च करती है, किंतु उतनी मात्रा में कर अथवा ऋण एकत्र नहीं करती है। इस प्रकार अतिरिक्त नोट छापने के फलस्वरूप सामान के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती।

महंगी होने वाली वस्तुएं : किन वस्तुओं पर कर का भारी बोझ पड़ने जा रहा है? ऐसा लगता है कि इस बार ऐसी वस्तुओं की लंबी श्रृंखला होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की रोजमर्रा की जिंसें भी होंगी। ऐसी चीजें जिन्हें आवश्यक जिंस कहा जाता है। मसलन कपड़ा, जूता, डबलरोटी, मक्खन, जैम,

टूथपेस्ट, विविध प्रसाधन सामग्री, नहाने-कपड़ा धोने के साबुन, खाद्य तेल, डिब्बाबंद आहार, बिजली और संभवतः खाना पकाने की गैस और किरासिन तेल।

इसके अलावा वह सामान, जिसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। इनकी भी संख्या काफी हो सकती है: रेडियो, टेलीविजन सेट खासकर रंगीन टेलीविजन और महंगे रेडियो, वीडियो सेट, रसोई में काम आने वाले बिजली के सामान, बिजली के पंखे, बल्ब, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर, धातु और चीनी मिट्टी के बरतन। जिन चीजों के दामों में भारी कर-वृद्धि की संभावना है, उनकी सूची में सबसे ऊपर नाम है परिवहन गाड़ियों का।

ऐसी बात नहीं कि इनमें से हरेक पर कर लगेगा, किंतु अनेक और शायद अधिकांश चीजें इसकी चपेट में आ जायेंगी। इसके साथ ही कर का अतिरिक्त बोझ ऐसी वस्तुओं पर पड़ेगा जो पारंपरिक रूप में इसकी परिधि में आती हैं। जैसे तैयार तंबाकू व सिगरेट, शराब, चाय और काफी। इस सूची को बढ़ाया भी जा सकता है, मगर इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरी सूची सरकार के कर-जाल में फंसने नहीं जा रही है, किंतु उनमें से अधिकांश का यही हश्र होगा।

डालडा
Dalda
डालडा
डालडा
Surf
Surf
Surf
Surf

अब आवश्यकता नहीं, विलासिता की चीजें!

इनमें से किन पर कर लगाया जायेगा या किन पर अधिक ऊंची दर पर कर लगाया जायेगा, दो बातों पर निर्भर करेगा—प्रधानमंत्री की राजनीतिक पसंद और हरेक जिस द्वारा मिलने वाले राजस्व-कर की वास्तविक मात्रा। दूसरा मुद्दा पहले लें। मान लें एक यात्री कार पर १० हजार रुपए अतिरिक्त राजस्व-कर लगता है। अब इस शुल्क से राजस्व-कर की इस प्रकार गणना करें:

इस वर्ष बिकी कारों की संख्या और अगले वर्ष की अतिरिक्त बढ़ी संख्या। इस कुल तादाद को १० हजार रुपए से गुणा कर दें। इस प्रकार आपको पता चल जायेगा कि कितना कुल अनुमानित धन आपको मिलने जा रहा है।

किंतु आपका अनुमान गलत हो जायेगा। जब कार की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जायेगी, तो बिकने वाली कार की संख्या में वृद्धि तो दरकिनार, उसमें और भी कमी होगी। इसलिए विभिन्न मूल्यों पर बिकने वाली कारों की तादाद में संभावित कमी और वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अनुसार ही आपको अपनी गणना करनी होगी। इसके अलावा दूसरा पक्ष भी है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तु में राजस्व-कर काफी अधिक हो सकता है भले ही कर की दर बहुत ऊंची न हो। मसलन, उन वस्तुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा जिनसे अधिक मात्रा में कर प्राप्त हो सकें। प्रतिमाह भेजे जाने वाले मनीआर्डर की संख्या १९६१ में ६६.८४ लाख थी, १९८४ में १ करोड़ ६ लाख व १९८५ में लगभग १ करोड़ ९५ लाख थी। मनीआर्डर द्वारा औसतन प्रतिमाह भेजे जाने वाली रकम १९६१ में २९.६२ लाख रुपए, १९८४ में १ करोड ५७ लाख रुपए और १९८५ में १ करोड़ ७० लाख रुपए थी।

मान लें १९८८-८९ में यह रकम बहुत ज्यादा यानी २ करोड प्रतिमाह हो और आप प्रति एक सौ रुपए अतिरिक्त फीस लगा दें, तो आपकी राजस्व प्राप्ति २ लाख रुपए प्रतिमाह और २४ लाख रुपए सालाना होगी। यह करदाताओं से उगाहने वाली रकम की तुलना में बहुत कम होगी। दूसरी ओर यदि हम गत कुछ वर्षों का ब्यौरा ध्यान में रखें, तो १९८८-८९ में रजिस्ट्रीशुदा पत्र व पार्सल की तादाद ३० करोड़ से कम नहीं होगी। यदि आप हर ऐसे पत्र और पार्सल पर मात्र एक रुपए अतिरिक्त वसूल करें, तो यह रकम ३० करोड़ रुपए सालाना से कम नहीं होगी। इसी प्रकार के जिंसों में से किसी एक का चुनाव आप समुचित मात्रा में कर प्राप्त करने के लिए करेंगे।

इस प्रक्रिया में सार्वजनिक उपभोग की

बजट क्या है?

बजट मुख्यतः किसी परिवार, व्यापारिक फर्म अथवा सरकार के आय-व्यय और बचत का एक ब्यौरा होता है। प्रत्येक परिवार इसी आधार पर एक महीने का बजट बनाता है। ऐसे निर्धनतम परिवारों की बात अलग है जिनके लिए कल के खाने का ठिकाना नहीं होता। बहरहाल, व्यवसायियों का बजट बनाए बिना काम नहीं चल सकता। यही बात सरकार पर भी लागू है।

सरकार की कमाई कुछ नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है। उसे करदाताओं से धन प्राप्त होता है अथवा वह बैंकों, फर्मों, निजी लोगों या विदेशी स्रोतों (सरकार या अंतरराष्ट्रीय बैंकों) से कर्ज लेती है। वह अपनी इस दूसरी अनन्य शक्ति का, जो मात्र उसे ही प्राप्त है, का (कर वसूली के अलावा) इस्तेमाल करती है। वह नोट छापती है और खर्च करती है, गोकि यह धन उसे किसी से हासिल नहीं होता। नये नोटों के रूप में यह अतिरिक्त रकम रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक कर्ज के रूप में जानी जाती है। इन स्रोतों के अलावा सरकार को ब्याज, किराया और मुनाफा से आय होती है। ब्याज ऐसी रकमों का जो उसने कर्ज के रूप में दी थी अथवा उस, अतिरिक्त राशि की प्राप्ति जो जनता को सेवा मुहैया करने वाले उसके विभागों पर होने वाले व्यय के एवज में होती है। मसलन टेलीफोन, डाक; रेलवे सेवा आदि।

बजट इस अनुमान के आधार पर बनाया जाता है कि सरकार को विभिन्न मदों के अपने खर्चों की भरपाई के लिए कितनी रकम की जरूरत है। उस धन को एकत्र करना पड़ता है। पहले करों से जो राजस्व कर कहलाता है। फिर दूसरे स्रोतों से जैसे किराया या मुनाफा। इस प्रकार राजस्व कर और गैर-राजस्व कर दोनों के योग का फल होता है—राजस्व की प्राप्ति। फिर सरकार देश के अंदर और विदेशों से कर्जे लेती है। जब इन सबके बाद भी जरूरत पूरी नहीं होती, तो सरकार नोट छापती है, जिसे 'घाटे की अर्थव्यवस्था' कहते हैं।

सरकार को १९८८-८९ के अपने कुल खर्च के लिए ६७,००० करोड़ रुपए चाहिए। सरकार अनेक वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर भी किसी स्थिति में ४०००० करोड़ रु० से अधिक एकत्र नहीं कर सकती। कर्ज लेकर भी वह १५००० करोड़ से अधिक रकम नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसी सूरत में तमाम दिमागी कसरत के बावजूद नया नोट छापकर कम से कम १० हजार करोड़ की घाटे की अर्थव्यवस्था अवश्यंभावी है।

वस्तुओं पर सर्वाधिक बोझ पड़ने की संभावना है। इससे सर्वाधिक प्रभावित गरीब लोग या ऐसे लोग होंगे जिनकी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि वह एक साल में अपने लिए एक जोड़ी जूता या अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी न खरीद सकें। दूसरा वर्ग जो बुरी तरह प्रभावित होगा वह है मध्यम वर्ग जिसकी मासिक आय १५०० से १०,००० रुपए के बीच है (हरेक आय-समूह को अलग-अलग स्थितियों का सामना करना पड़ता है और जो इस पर निर्भर करता है कि उसकी उपभोग-वस्तुओं की कीमत क्या है)। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की अनगिनत वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ सहना पड़ेगा। यह राजस्व शुल्क हो या तट कर (मुख्यत: आयात) यह अहम सवाल नहीं है। इसके साथ-साथ इस मसले को देखते हुए कि कौन कितना कर अदा कर सकता है और किस सामान को दूसरों की तुलना में महंगा करना चाहिए। इस दृष्टि से ऐसे सामानों पर कर लगाना चाहिए जिसका व्यापक उपयोग धनी अथवा 'संपन्न' कहलाने वाला मध्यमवर्ग करता है। इसका अर्थ है, वे लोग जो टिकाऊ उपभोक्ता सामान मसलन-रंगीन टीवी, वीडियो सेट, यात्री कार जैसी वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे और सामान कुछ कम आय वाले परिवार के लोग भी खरीदते हैं। महंगी शराब, कीमती इत्र-फुलेल आदि। इस प्रकार ऐसे अनेक सामानों पर पर्याप्त कर लगाया जा सकता है। यह सब मिलजुल कर अच्छी खासी राजस्व राशि एकत्र कर सकते हैं।

दखलंदाजी: इसी मामले में सरकारी नीति का दखल होता है। एक है उसकी आर्थिक नीति, दूसरा और अधिक निर्णायक है राजनीतिक नजरिया। अभी तक सरकारी नीति ऐसे सामानों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है जिसका प्रयोग संपन्न या धनी परिवार करते हैं। यह उद्योगपतियों के अनुकूल होता है, क्योंकि वे अपनी वस्तुएं ऊंची कीमत और भारी मुनाफे पर बेच सकते हैं। 'उदारीकरण की नीति' के नाम से प्रख्यात नीति ऐसे सामानों के साथ अधिक पक्षपात बरतती है।

ऐसी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से मांग कम हो जायेगी, गोकि ऐसे सामानों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। मसलन, स्कूटर व यात्री कार की अब उतनी मांग नहीं है जितनी एक साल पहले थी। यही बात सिंथेटिक कपड़ों या सिलेसिलाये वस्त्रों, रंगीन टीवी, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि पर भी लागू है।

किंतु यदि ऐसे सामानों पर कर नहीं लगा और केवल सार्वजनिक उपयोग की चीजें महंगी हुई, तो राजीव गांधी पर फिर यह इलजाम लगेगा कि उनकी सरकार धनिकों और संपन्न लोगों की पक्षधर है। यह स्थिति तब और विकट होगी जबकि आम चुनाव बहुत दूर नहीं। अब महज एक वर्ष नौ महीने रह गये हैं।

इसलिए सरकार को धनी और खुशहाल, मध्यमवर्ग पर कर लगाना होगा। हरेक को ज्यादा रकम अदा करनी पड़ेगी। धनी और संपन्न लोगों को अधिक आय कर देना होगा। उन्हें उन कई वस्तुओं के लिए अधिक कीमत देनी होगी जिनका केवल वे ही इस्तेमाल करते हैं (देखें सूची)।

नतीजतन चतुर्दिक मूल्यवृद्धि अवश्यंभा है। पहला, क्योंकि सामानो पर अतिरिक्त कर लगेगा और फिर इसलिए कि उन सामानों की अधिक ऊंची कीमत से मूल्यवृद्धि होगी। किंतु मूल्यवृद्धि की ऊंची दर से सरकार का अपना खर्च बढ़ जायेगा। इसमें बहरहाल, कुछ महीने लगेंगे—जैसे तब जब सरकार को अपने कर्मचारियों को ज्यादा महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। शायद तब अधिक कर लागू होंगे यांनी सितंबर या उसके बाद में। यह भी संभव है कि सरकार वर्ष के अंतिम दिनों में अधिक नोट छापे। ये कदम 'पूरक-मांगों' के नाम से माने जाते हैं। इसलिए पूरक-मांगें इस बार काफी ऊंची हो सकती हैं जिससे अधिक कर और अधिक घाटे का बजट फिलहाल नजर न आये। इस प्रकार संभव है कि कर का बोझ वर्ष के विभिन्न भागों में बांट दिया जाये। यह पहले ही किया जा चुका है। सरकार ने पेट्रोल, लोहा, कोयला, चीनी का दाम बजट से पहले ही बढ़ा दिया है। विचार यह है कि इसे बजट के प्रभाव के रूप में न प्रतीत होने दिया जाये।

—कुमारेश चक्रवर्ती

अतिरिक्त कर के चपेट में आने वाली जिंसें

जिन पर सितारे का चिन्ह है, वे असली निशाना बनेंगी

उत्पाद कर

*बरतन (धातु और प्लास्टिक)
*चाय
काफी
*बिजली के पंखे
*बिजली के लैंप
चीनी
*जूते
साबुन
*सिगरेट
*पान मसाला
फिल्म
*सेनेटरीवेयर
*लकड़ी के बने सामान
स्टोव
*टूथपेस्ट
*खाना पकाने वाली गैस
फाउंटेन पेन और पैंसिलें
*मोटर-कार
दोपहिया वाहन
*टायर
रंगीन टी०वी०
*वीडियो सेट्स
*एयर कंडीशनर
रेफ्रीजरेटर
*सौंदर्य प्रसाधन
*सायकिल
*चमड़े के सामान
*कंप्यूटर
*कलकुलेटर
*वर्ड प्रोसेसर्स
*इलेक्ट्रिक टाइपराइटर
रेडियो
*फ्लोर टाइल्स
*ट्रैक्टर
*दीवार-घड़ी
घड़ियां
*ऊनी वस्त्र
*डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड)
*सनफ्लावर तेल
*कार्न आयल
राइस ब्रान आयल (धान तेल)

सीमा कर

आटोमोबाइल के उपकरण
उद्योग संबंधी रसायन
केरोसीन आयल
इलेक्ट्रानिक के सामान

जैट
और
बोस्की
सिर्फ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS.

लीला मिश्रा

अभिनय को जिंदगी की तरह जिया

अभाव खलेगा: लीला मिश्रा

फिल्म इंडस्ट्री में 'मौसी' नाम से विख्यात लीला मिश्रा ने अपने फिल्म अभिनय जीवन की शुरुआत १९३६ से की थी। दादा साहब फालके की एक फिल्म में मां की भूमिका निभानेवाली अभिनेत्री अचानक बीमार पड़ गयी, तो काम की तलाश में स्टूडियो का चक्कर लगानेवाली लीला मिश्रा को दादा साहब फालके ने मां की भूमिका दे दी और उनका पहला दृश्य एक ही 'शाट' में ओ०के० हो गया। उन्होंने 'गंगावतरण' में नायिका की भूमिका भी निभायी, लेकिन फिल्म के बाक्स आफिस पर फ्लाप हो जाने के कारण वह भरी जवानी से ही मां, बहन, दादी, भाभी की चरित्र भूमिकाओं में ही सिमट कर रह गयीं। 'शोले' में निभायी मौसी की भूमिका के बांद वह सभी फिल्मवालों के लिए 'मौसी' बन गयीं। उन्होंने बिलिमोरिया, रूसी मायर्स, मास्टर विसार की बीती पीढ़ी से लेकर दिलीप कुमार, राजकपूर, अशोक कुमार, देवआनंद और नयी पीढ़ी में गोविंदा, नीलम और फरहा तक के साथ काम किया और ४०० से अधिक फिल्मों में तरह-तरह की भूमिकाएं निभायीं। 'अनमोल घड़ी', 'एलान', 'जीवन ज्योति', 'शिकस्त', 'शोला और शबनम', 'राखी', 'राम और श्याम', 'सीता और गीता', शोले', 'मनपसंद', 'दोस्ती', 'लाजवंती', 'गीत गाता चल', 'कथा', 'चश्मेबद्दुर', 'शतरंज के खिलाड़ी', दुल्हन वही जो पिया मन भाये', 'दुश्मन', प्रेम रोग' आदि फिल्में उनके सशक्त अभिनय के लिए याद की जायेंगी। निर्देशिका सई परांज़पे के अनुसार, "मैं तो मौसी के बिना किसी फिल्म के बारे में सोच ही नहीं सकती थी।"

वह ५१ वर्ष तक बंबई में रहीं, लेकिन शिवाजी पार्क के जिस चालनुमा मकान में रहने आयीं, वहीं मृत्युपर्यंत रहीं। भोजपुरी बोलने का लहजा तथा खान-पान, पहनावा और आदतों में एक इंच का भी फर्क नहीं आया। उनके जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना सत्यजित राय की फिल्म में काम करने की थी और राय ने 'शतरंज के खिलाड़ी' के लिए सबसे पहले उन्हीं को अनुबंधित किया था।

शूटिंग पर स्टूडियो पहुंचते ही वह कोलाहल का केंद्र बन जाती थीं, नयी-पुरानी पीढ़ी के लोग उनके पैर छूते, लेकिन उनकी शवयात्रा में कंधा देने के लिए दिलीप कुमार से लेकर गोविंदा तक कोई नहीं आया।

वह जिस भी स्टूडियो में शूटिंग कर रही होतीं, उन्हें घेर कर यूनिट के लोग जरूर बैठे रहते। गपें मारने और लोगों को हंसाने का उनको बड़ा शौक था। पान-पर-पान खाती जातीं और नये-पुराने क़िस्से सुनाती जातीं। शूटिंग का बुलावा आता, तो तुरंत उठ कर चली जातीं और शाट देने के बाद फिर आकर गप-मंडली का संचालन करने लगतीं। वाकई जिस सहजता से वह कैमरे के सामने काम करती थीं, वह आश्चर्यजनक थी। बड़े से बड़ा अभिनेता शाट में गड़बड़ी कर सकता था, मगर लीला मिश्रा की वजह से 'रिटेक' करना पड़े, ऐसी शिकायत कभी नहीं सुनायी दी।

फिल्म 'राम और श्याम' में वह दिलीप कुमार की मां बनी थीं, जो अपने आवारा लड़के को डंडे से मारती-धकियाती कमरे में बंद कर देती है। यह दृश्य कामेडी के लिहाज से भी काफी उपयुक्त था। दिलीप कुमार में यह खास बात है कि वह हर सीन में इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनका सहयोगी अभिनेता या अभिनेत्री उनके मुकाबले कहीं ज्यादा महत्व न ले जाये। लीला मिश्रा के बारे में कभी उन्होंने कहा था, "बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। उनके सामने बड़े-से-बड़े आर्टिस्ट को अहसास-ए-कमतरी महसूस हो सकती है। बहुत ही नेचुरल ऐक्टिंग करने में...।"

ग्लैमरस और देहाती मां का जो रूप लीला मिश्रा ने परदे पर प्रस्तुत किया, उसे अपने असली जीवन में जिया भी। फिल्मों में उनकी हमेशा मांग बनी रही, मगर किसी भी निर्माता से उन्होंने अपने पारिश्रमिक को लेकर कभी कोई कटु वाद-विवाद नहीं किया। उनका रहन-सहन भी बहुत ही साधारण था। फिल्मी कलाकारों जैसे दिखावों से वह कोसों दूर थीं।

बंबई जैसे माहौल में पूरे पचास वर्षों तक वह अपने देहातीपने से लिपटी रहीं। भारतीय परिवार की नानी-दादी का प्रतिनिधित्व उन्होंने जिस खूबी से किया, अब ऐसा कोई कलाकार कर सकेगा, इसमें संदेह है। उनके व्यक्तित्व की तरह उनके अभिनय में भी हास्य-विनोद की छाया हमेशा मौजूद रही। टी०वी० विज्ञापनों में नानी-दादी के रूप में जब भी वह मात्र दस सेकेंड के लिए आयीं, तो हर देखनेवाले को यह जरूर महसूस हुआ होगा कि वह अपने ही परिवार की दादी या नानी की सलाह सुन रहा है। टी०वी० सीरियल 'दादा-दादी की कहानी' में उन्होंने अभिनय कहां किया, दर्शकों को ज्ञात भी नहीं हो सका। यों फिल्मों में भी उन्होंने वही किया, जो वास्तविक जीवन में जिया। अभिनेता कन्हैयालाल का जो अभाव आज फिल्म उद्योग में महसूस हो रहा है, वैसा ही लीला मिश्रा के बाद महसूस होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

—बंबई ब्यूरो, हरीश तिवारी

मनोरमा

फरवरी द्वितीय पक्ष

होली विशेषांक

हास्य-व्यंग्य और रंग-रस से सराबोर रचनाएं

आवरण कथा :

जब उनका मिजाज आशिकाना हो

आशिक मिजाज, यानी मुहब्बत करनेवाला शौहर पाना
भला किस पत्नी की ख्वाहिश न होगी,
पर आशिकमिजाजी हद से ज्यादा बढ़ जाये तो पत्नी बेचारी
मुश्किल में पड़ जाती है।

विशेष रचनाएं

'जब गधे को बाप बनाना पड़ा' आपबीती सुनिए—ठाकुर प्रसाद सिंह, संतोष खरे, निर्भय हाथरसी, डा० सुरेशव्रत राय, डा० देवीप्रसाद कुंवर, फज्ले हसनैन, असित सेन और राकेश बेदी से।

'जब श्रीदेवी आ जाएं
आपके पति से खेलने होली',
फागुनी परिचर्चा

रोचक लेख :
'होली है ठिठोली है,
यानी फ्लर्टिंग देवर- जीजा से'

फिल्म : खेलो रंग हमारे संग...

हास्य व्यंग्य :
फिर अइयो खेलन होली कम्प्यूटर लला

व्यंजन : पर्व पर बनाइए रंग-बिरंगे तीखे-मीठे व्यंजन

सुहागरात : 'कमरा ठीक से सजा है न ?'

फैशन : रंग-रंगीले परिधान

मेकअप : अपना खोया सौंदर्य जगाइए

कहानी : शादमा अंजुम की मार्मिक कहानी 'मंजिल'

अन्य सभी स्थायी स्तम्भ व अनेक पठनीय रचनाएं

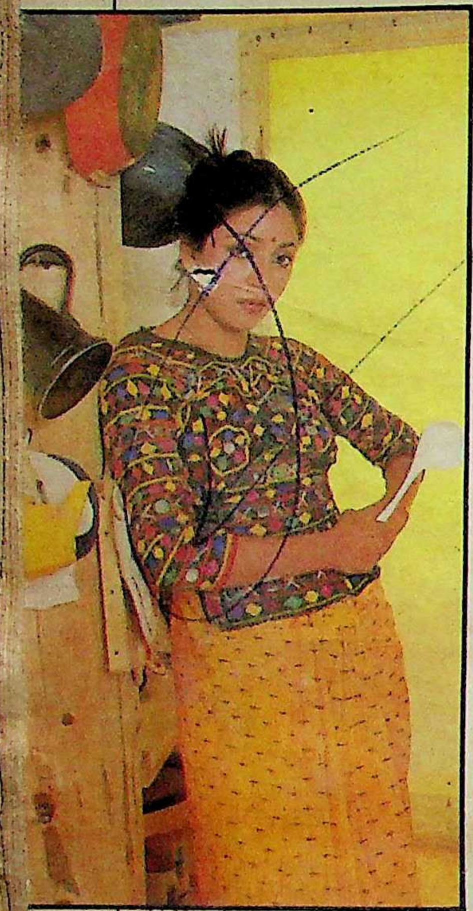

दीप्ति नवल

छाया: तैयब बादशाह

उनकी पत्नियां भी उन्हें तलाक दे-दे कर मिसाल कायम करने में पीछे नहीं रहीं। बिंदिया की बेवफाई ने उनका दिल कुछ इस तरह तोड़ा कि काजल किरण, शोमा आनंद से लेकर जयाप्रदा तक उनमें विवाह की लगन नहीं जगा सकीं। उनके बचपन के साथी तथा सहपाठी विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही जब अपने रोमानी संबंधों की इहलीला शुरू कर दी, तो विनोद मेहरा भी जागे। नींद भी खुली, तो सात समंदर पार। बार-बार के लगन-वाकयों से सबक ले इस बार वह अपने लिए दुल्हन लाये कीनिया से। सिख विनोद मेहरा ने मोम्बासा में जन्मी, कीनिया में पढ़ी-लिखी-बड़ी हुई सरदारनी किरण ग्रेवाल से मकर संक्रांति (१४ जनवरी' ८८) को सिख पद्धति से विवाह कर पालीहिल (बांद्रा) के उस सूने पड़े बंगले में पुनः रौनक बिखेर दी, जिसे बतौर ताजमहल उन्होंने बिंदिया गोस्वामी के लिए बनाया था।

दीप्ति का अकेलापन

अपने कविगुरु गुलजार की सहायता से, लंदन से नयी-नयी आयी दीप्ति नवल ने अपना काव्य संग्रह 'लम्हा-लम्हा' तो प्रकाशित करवा लिया, लेकिन उनकी फिल्मों में कोई रोल हासिल नहीं कर सकी। 'एक बार फिर' के खलनायक पति (सुरेश ओबेराय) से न तो वह ताजिंदगी अपने को जोड़ सकी और न ही लंदन के दोस्त-हीरो प्रदीप वर्मा (चिकने-चुपड़े चेहरेवाले फारूख शेख) और न ही एक और लंदन-पलट ही-मैन (मार्क जुबेर) दीप्ति की जिंदगी में प्रेम का रंग घोल सके। बिहारी बाबू प्रकाश झा भी दीप्ति को मातृत्व की चिर-आकांक्षित खुशियों की बहार नहीं दे सके। फलतः दीप्ति ने अपनी जैसी ही बिखरी जिंदगी वाली सहेली निर्देशिका-निर्मात्री सई परांजपे के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है।

'चश्मेबद्दूर' और 'कथा' फिल्मों के दौरान वह फारूख की जिंदगी में कुछ इस गहराई तक उतर गयी कि फारूख का खुद का दांपत्य जीवन तनावपूर्ण हो गया। दूसरी तरफ दीप्ति का पारिवारिक जीवन इतना कुंठाग्रस्त होता गया कि दीप्ति और प्रकाश को उनका घर काटने के लिए दौड़ने लगा। फलतः वर्ष के १२ महीनों में दस महीने दीप्ति नवल लंदन में मां-बाप के पास और प्रकाश दिल्ली और पटना में रहकर कभी टेलीफिल्म या डाक्युमेंट्री बनाते हैं, तो कभी दिल्ली में विशालकाय फिल्म स्टूडियो बनाने के सपने देखते हैं। शेष दो महीने वे दोनों बंबई में होते हैं, लेकिन बमुश्किल किसी शाम एक-दूसरे का साथ हो पाता है।

अपने अकेलेपन से त्रस्त दीप्ति ने कविगुरु गुलजार से दोस्ती पुनः गांठकर शायरी करनी तथा रसोई घर में कुछ घंटे गुजारना शुरू कर दिया है।

पाली (हिल) वुड के रिचर्ड बर्टन!

एशिया के हालीवुड (बंबई) के विनोद मेहरा ही एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो असली हालीवुड के रिचर्ड बर्टन से प्रेम और विवाह के मामले में टक्कर ले सके। यों तो दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की प्रेमकहानियों का कोई जवाब नहीं, फिर भी इनमें से किसी ने अपनी प्रेमिकाओं का हाथ थामने की हिम्मत नहीं दिखायी। विनोद मेहरा भी शुरू-शुरू में मौसमी से विवाह करने में थोड़ा जरूर डगमगाये, लेकिन जब वह बोल्ड हुए, तो बिंदास मौसमी पीछे हट गयी। लेकिन इस 'बोल्डपने' ने मासूम से दिखने वाले विनोद मेहरा में हिम्मत और लगन की ऐसी अमोघ शक्ति भरी कि वह कभी अभिनेत्री तो कभी गैरअभिनेत्री से लगन के फेरे और तलाक लेते गये। रेखा से लेकर बिंदिया गोस्वामी तक से विवाह की नयी-नयी मिसालें कायम करते रहे।

छाया: दुर्गाप्रसाद

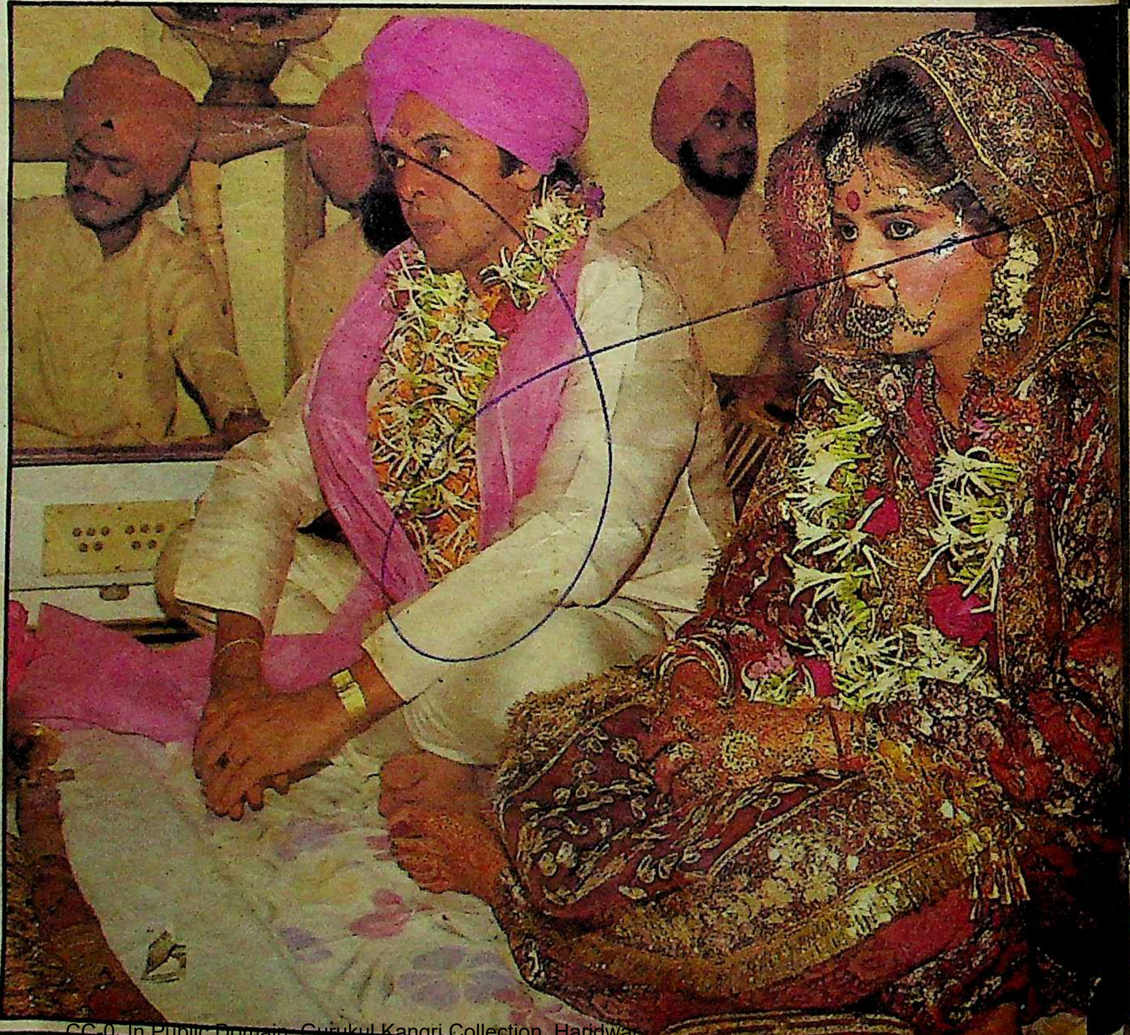

विनोद मेहरा एवं किरण ग्रेवाल

सानिया

सानि

'घ

से बेजार
खोज सानि
उसका ए
गया उनके
जबरदस्त
इस 'कश्मी
"देव आनं
चुंबन लिय
है। वह ज
करती है,
परेशान हो
तो वह अ
नजर ही
सिर्फ उनक
स्वीकारोक्ति
इंडस्ट्री में
दिया है।
धंधा ही स
(अश्लील
तो वही अ
लिए तैया

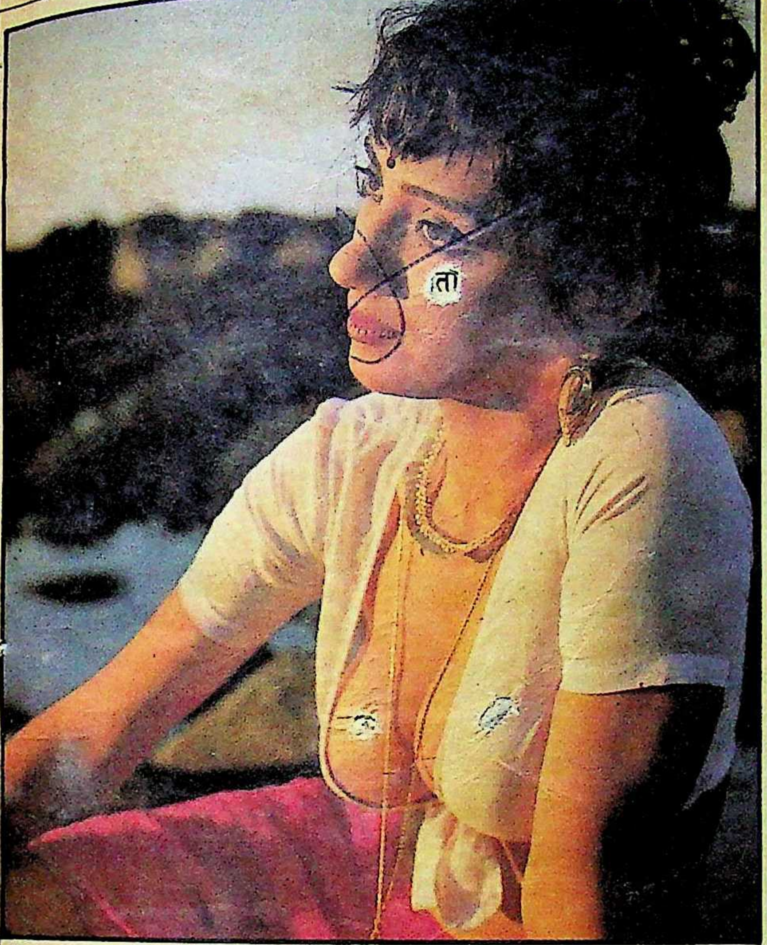

सानिया

छाया: डी०आर० यादव

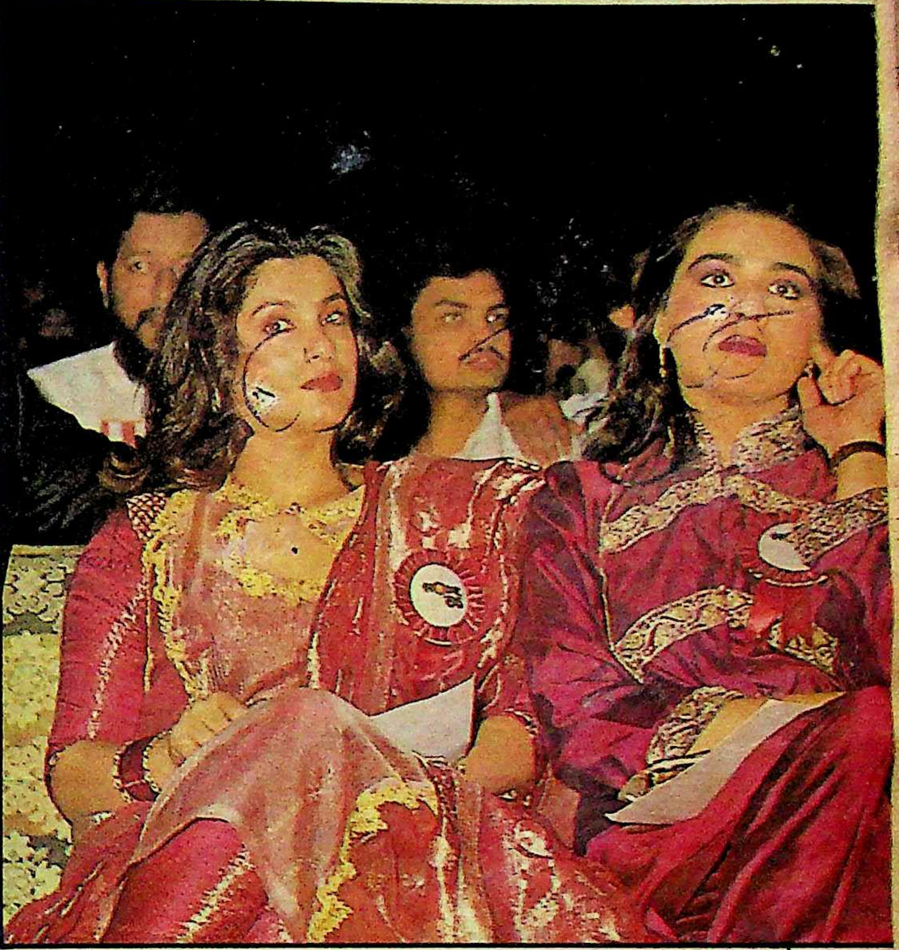

छाया: धर्म मूलचंदानी

अमृता सिंह, डिंपल

सानिया का जलजला

'घर को आग लग गयी घर के चिराग से!' वाली कहावत से बेजार देव आनंद अपनी ही नयी खोज सानिया से बेजार हैं, कारण है उसका एक गाशिप-पत्रिका में दिया गया उनके तथा दूसरों के बारे में जबरदस्त साक्षात्कार। १६ वर्ष की इस 'कश्मीरी कली' का कहना था; "देव आनंद ने कार के भीतर उसका चुंबन लिया, वह सिर्फ देव आनंद की है। वह जब दूसरों के साथ शूटिंग करती है, तो वह (देव) ईर्ष्या से परेशान हो जाते हैं। उनका बस चले तो वह अपने सिवा किसी और की नजर ही न पड़ने दें उस पर। वह सिर्फ उनकी है...।" सानिया की इस स्वीकारोक्ति ने बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जलजला-सा पैदा कर दिया है। उसका कहना है, "यहां का धंधा ही खुले बदन और खुली भाषा (अश्लील गालियां देने) का है। यहां तो वही आता है जो 'हर काम' के लिए तैयार हो।...मैं यहां केवल वह करने के लिए तैयार हुई हूं जो इंडस्ट्री की हर ऐक्ट्रेस आज धड़ल्ले से कर रही है। मैं सब बोल देती हूं और सब कर देती हूं। दूसरी नायिकाएं बोलती कुछ नहीं, मगर करती सब कुछ हैं।" उसके इस कथन से सारी फिल्म अभिनेत्रियां नाराज हो उठी हैं। साथ ही चंकी पांडे से लेकर हेमंत बिरजे तक अब उसके साये से भागते नजर आते हैं, क्योंकि उसने उन्हें भी उनके अंतरंग कृत्यों के लिए बेनकाब करने में कोई कोताही नहीं बरती है।

स्वामीजी की संगत

डिंपल और अमृता सिंह ने ३५-३५ दिन के दो लंबे शिड्यूलों में फिल्म 'बंटवारा' के लिए जयपुर में शूटिंग क्या की कि दोनों का जैसे काया-पलट ही हो गया। फिल्म निर्माता ने जब दोनों को साइन किया था, तो समूची फिल्म इंडस्ट्री में यह अफवाह फैल गयी थी कि एक-दूसरे का चेहरा न देखने की कसम खानेवाली ये अभिनेत्रियां अपने आपसी झगड़े में फिल्म का ही बंटवारा कर देंगी। निर्देशक ने इस आशंका को ध्यान में रखते हुए दोनों की अलग-अलग लोकेशनों पर शूटिंग की और इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा कि वे न तो फिल्म के एक सीन में एक दूसरे के आमने-सामने हों और न असल जिदगी में, इसलिए उनको अलग-अलग ठहराया। उस समय जरूर संकट पैदा हो गया जब दोनों खाली समय बिताने के लिए स्वामीजी (विनोद खन्ना) के सुइट में पहुंच गयीं लेकिन स्वामीजी ने इसका हल निकाल ही लिया।

इन दोनों अभिनेत्रियों की आपसी दुश्मनी के कारण हैं—सन्नी देवल एवं अमिताभ बच्चन। अमृता सन्नी की प्रथम हीरोइन होने के कारण उस पर अपना पहला हक मानती थी, लेकिन डिंपल ने उसे वहां से ऐसा बेदखल किया कि 'जी से गये अरमां से गये' कहावत वाली अमृता ने डिंपल के विरुद्ध अपनी 'जबानी मर्दानगी' दिखानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ डिंपल किसी भी शर्त पर 'मर्द' में अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनना चाहती थी। उसने बाप-बेटे (मनमोहन देसाई और केतन देसाई) दोनों को राजी कर लिया था, सवाल अमिताभ की रजामंदी का था, जो डिंपल के साथ काम करने की तीव्र लालसा के बावजूद राजेश खन्ना के कारण हिचक रहे थे। उनकी इसी हिचकिचाहट को 'कैश' कर वह भूमिका अमृता सिंह ने,न केवल झपट लिया, बल्कि उनकी नवीनतम फिल्म 'तूफान' की भूमिका भी हथियाने में सफल रही, जो विशेष रूप से डिंपल के लिए लिखी गयी थी।

दोनों अभिनेत्रियों के बीच छीना-झपटी का यह चक्रव्यूही द्वंद्व और चलता कि स्वामीजी के सान्निध्य ने उनका ऐसा कायापलट कर दिया कि जयपुर से वापसी के बाद दोनों एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधने लगीं। डिंपल ने तो राजेश खन्ना की फिल्म 'जय शिव शंकर' में संगीता बिजलानी वाली भूमिका अमृता को दिलाने की पुरजोर कोशिश भी की। अंततः राजेश खन्ना को अगली फिल्म में उसके साथ काम करने के लिए राजी करा लिया।

—अखबारी लाल

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी ख़ुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्ज़ाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
CONTAINS VITAMINS
100 ml.
CONTAINING PROTEIN, VITAMINS AND CO-ENZYMES
DEY'S MEDICAL STORES LTD.

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना

फिर से जुड़ने की भूमिका ?

दस वर्षों तक तनातनी का वैवाहिक जीवन व्यतीत करने और चार वर्षों से नदी के दो किनारों की तरह अलग-अलग रहने वाले राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अपनी बेटी के प्रयास से फिल्म 'जय शिव शंकर' में एक हो गये हैं। इस फिल्म में राजेश खन्ना की हीरोइन डिंपल हैं। क्या यह फिर से दोनों के जुड़ने की भूमिका है ?

क्या कड़वाहट मिट सकेगी ?: मिठाइयां खिलाकर बधाई देते हुए डिंपल और राजेश खन्ना

छाया : रायंजन घटक

लगभग दस वर्षों के दांपत्य तथा चार वर्षों के अलगाव की जिंदगी के बाद राजेश खन्ना और डिंपल के बीच तनाव और मतभेद की दीवार पहली बार ८ जनवरी, १९८८ को सार्वजनिक रूप से टूटी—जब दोनों 'जय शिव शंकर' फिल्म में नायक-नायिका की भूमिका निभाने के लिए सेट पर आये और एक-दूसरे को मिठाई खिला कर बधाइयां दीं। इस फिल्म के निर्माता खुद राजेश खन्ना हैं और बकौल राजेश खन्ना डिंपल ने उनसे फिल्म की हीरोइन की भूमिका जबरदस्ती छीन ली, हालांकि इसके लिए वह अनुराधा पटेल को साइन कर चुके थे। राजेश खन्ना इसे मजाक में ही सही, डिंपल की 'इमोशनल ब्लैकमेलिंग' मानते हैं, जिसके सामने वह लाचार हो गये।

राजेश खन्ना-डिंपल के बीच तनाव और अलगाव राजेश खन्ना की अतिव्यस्तता के बीच डिंपल के अकेलेपन के कारण हुआ था। एकाकीपन की त्रासदी से डिंपल को बचाने के लिए चुन्नी भाई कपाड़िया और राजेश के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी थी कि वह वर्ष में कम-से-कम एक फिल्म डिंपल के लिए बनायें, जिसमें अपने साथ हीरोइन की भूमिका डिंपल को दें। इससे डिंपल का अकेलापन भी खतम हो जायेगा और अभिनय न करने से उसके मन में जो कुंठा है, वह भी खतम हो जायेगी। लेकिन तब राजेश खन्ना ने इस बात को मखौल में उड़ा दिया था।

दोनों ने अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री में नये सिरे से अपने भाग्य की आजमाइश शुरू कर दी। २५ वर्षीया डिंपल के साथ जहां दो बच्चियों के मां का तमगा लगा हुआ था, वहीं राजेश खन्ना फ्लाप हीरो के रूप में आउट-से हो चुके थे। डिंपल की वापसी जहां जोर-शोर से शुरू हुई और उसके घर निर्माताओं की लाइनें लगने लगीं, वहीं राजेश खन्ना के पास चंद इने-गिने फिल्म निर्माता भर थे। डिंपल के आशीर्वाद (राजेश खन्ना का घर) छोड़ते ही जैसे राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश से उबर गये और उनकी 'अवतार' बाक्स आफिस पर सुपर हिट हुई, दूसरी तरफ डिंपल की 'सागर', 'पाताल भैरवी', 'लावा', 'मंजिल-मंजिल', 'ऐतबार', 'अर्जुन', 'अल्लारखा', 'जांबाज', जैसी फिल्में लगातार पिटती चली गयीं। लेकिन फिल्मों की असफलता के बावजूद रमेश सिप्पी से लेकर सन्नी देवल के साथ अफेयरों ने हमेशा उसे सुर्खियों में रखा। दूसरी तरफ टीना मुनीम के कारण राजेश खन्ना भी हमेशा सुर्खियों में बने रहे।

साक्षात्कार/राजेश खन्ना

डिंपल ने रोल छीन लिया!

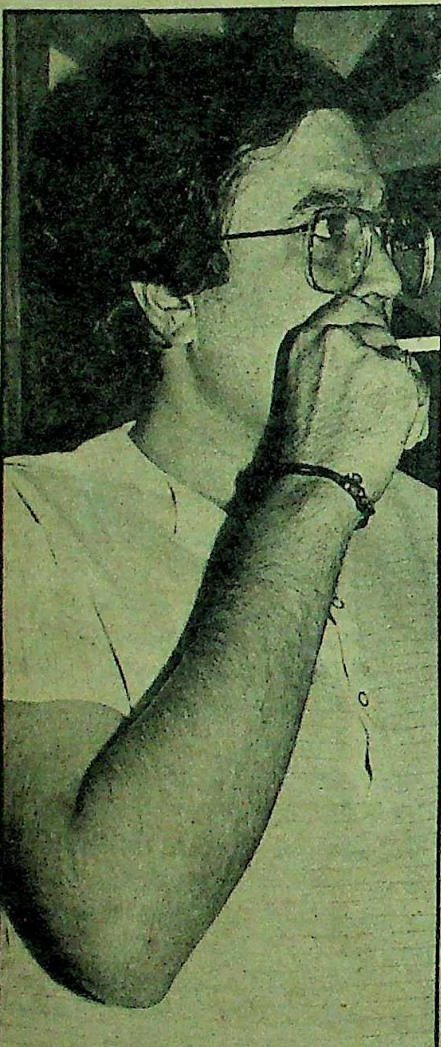

फिल्म इंडस्ट्री में बेहद 'श्रूड' मानेजाने वाले राजेश खन्ना राजनीति में प्रवेश करने के बावजूद खामोश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। डिंपल से अलग होने के बाद लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन वह हर बार खामोशी भरी चुप्पी ओढ़ जाते थे। यही चुप्पी उन्होंने 'जय शिव शंकर' फिल्म के मुहूर्त के समय भी ओढ़ रखी थी और असली जीवन में उनके विरुद्ध जाहिराना तौर पर उठ खड़ी हुई डिंपल भी उन्हीं का अनुसरण करती रही। लेकिन राजेश खन्ना ने डिंपल के उनकी फिल्म में काम करने के बारे में पहली बार खुलकर 'माया' से बात की। प्रस्तुत हैं, 'माया' से उनकी बातचीत के कुछ अंश:

माया: तो आप दोनों में अंततः समझौता हो ही गया?

राजेश: कैसा समझौता?

माया: यही कि डिंपल और आपके बीच के मतभेद खतम हो गये और डिंपल के वापस 'आशीर्वाद' लौटने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो गयी हैं।

राजेश: इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मेरे विचार से यह सिर्फ एक 'प्रोफेशनल' समझौता है, हमारी, निजी जिंदगी से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

माया: तो डिंपल सिर्फ आपकी फिल्म की हीरोइन भर है?

राजेश: हां, सिर्फ हीरोइन। तीन हीरोइनों में से एक। शेष दो हैं—पूनम ढिल्लों तथा संगीता बिजलानी। यह तीन नायकों—जय, शिव और शंकर (राजेश खन्ना, जीतेंद्र और चंकी पांडे) की कहानी है, लेकिन नायिकाओं की भूमिका भी इसमें काफी अहम है।

माया: सुना है, डिंपल वाली भूमिका पहले अनुराधा पटेल निभानेवाली थी?

राजेश: हां, अनुराधा पटेल के नाम की पब्लिसिटी-डिजाइन तक तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह डिंपल आ गयी।

माया: इससे आपकी फिल्म की सेलिंग कास्ट बढ़ गयी, जो अनुराधा पटेल के होने से संभव नहीं थी।

राजेश: हां, एक हद तक ठीक है, लेकिन यह कोई विशेष मायने नहीं रखता।

माया: लेकिन जब आपका सारा प्रोजेक्ट तय था, तो आपको अचानक अनुराधा पटेल को बदल कर डिंपल को ले लेने की कैसे सूझी?

राजेश: मुझे नहीं सूझी।

माया: क्या मतलब?

राजेश: मैंने उसे कोई रोल नहीं आफर किया। मौजूदा हालात में रोल आफर करने के बारे में सोचने की बात ही नहीं उठती थी। उसने खुद मेरी फिल्म में काम करने की इच्छा प्रकट की।

माया: यह असंभव बात संभव कहां और कैसे हुई?

राजेश: यहां नहीं, यहां से बहुत दूर नैरोबी में सारा कुछ फाइनल हुआ। मैं उस समय लंदन गया हुआ था। वह दोनों बेटियों के साथ दारस्सलाम गयी हुई थी। उसी दौरान ट्विंकल का जन्मदिन पड़ा। ट्विंकल ने मुझे लंदन फोन कर कहा—"पापा, क्या मेरा जन्मदिन भूल गये आप?" मैंने कहा—"वाह भला अपनी बिटिया का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूं। ऐसा करो, तुम लोग नैरोबी पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूं। वहीं पर तुम्हारा जन्मदिन मनायेंगे।"

माया: कितने दिनों बाद मिले थे आप अपनी बच्चियों से?

राजेश: काफी दिनों बाद। अपनी बच्चियों को देखे हुए मुझे काफी समय हो गया था, सच कहूं तो मैं उन्हें देखने के लिए तरस गया था। ट्विंकल से बात होते ही मैं दूसरे दिन नैरोबी पहुंच गया।

माया: फिर डिंपल से फिल्म की बात कैसे चली?

राजेश: यों ही। उसने मुझसे पूछा, "आजकल क्या कर रहे हो?" मैंने बतला दिया, "साउथ की एक सुपर हिट फिल्म के अधिकार हिंदी री-मेक के लिए खरीद लिये हैं। उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं। एस० चंद्रशेखर को डायरेक्ट करने के लिए साइन कर लिया है।" मैंने उसे कास्टिंग और कहानी के बारे में भी विस्तार से बतलाया। पूरी कहानी सुन कर कुछ देर सोचने के बाद वह एकबारगी बोल उठी—"तुम्हारे साथ की हीरोइनवाला रोल मैं करूंगी।"

माया: लेकिन आप तो अनुराधा पटेल को उस रोल के लिए साइन कर चुके थे। आपने मना नहीं किया?

राजेश: मैंने उसे कास्टिंग फाइनल करने के बारे में भी बतला दिया, लेकिन वह रोल करने के लिए जिद्द पर अड़ गयी—"नहीं, यह रोल तो मैं ही करूंगी।" मेरे यह कहने पर कि 'तुम मेरी फिल्म के लिए डेट्स नहीं निकाल सकती', वह बोली, "जब की डेट्स चाहोगें, तब की मिल जायेगी।" मैं अजीब धर्मसंकट में फंस गया। मुझे दुविधा में पड़ा देख उसने कहा—"यह फिल्म किसलिए बना रहे हो, पैसा कमाने के लिए न? पैसा किसलिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए ही न! तो जो फिल्म मेरे बच्चों के हित के लिए बनायी जा रही है, भला मैं उसमें कैसे काम नहीं करूंगी?" डिंपल के इस तर्क के सामने मैं लाजवाब हो गया, फिर रही-सही कसर उसने यह कह कर पूरी कर दी—"मैं इस फिल्म के काम के लिए एक पैसा भी नहीं लूंगी...!"

माया: अंततः जिस तरहं आप लोग एक साथ काम करने के लिए राजी हो गये, एक दिन पुनः विवाह कर घर भी बसा सकते हैं?

राजेश: ऐसा 'इंपासिबल' है।

माया: क्यों? क्या आप दोनों पुर्नविवाह कर अपने टूटे हुए दांपत्य जीवन को पुनः नहीं बसा सकते और बच्चों को मां-बाप का प्यार नहीं दे सकते?

राजेश: हम दोनों में तलाक हुआ ही कहां है कि फिर से शादी का सवाल उठे। हम दोनों आज भी कानूनन पति-पत्नी हैं। हम दोनों अपनी लड़कियों को भरपूर प्यार देते हैं, उन्हें कभी भी मां-बाप के प्यार की कमी नहीं खलने पायी। रही डिंपल की बात, तो वह कभी भी बच्चियों को लेकर मेरे घर आ सकती है, यों भी बच्चियों को लेकर अकसर आती ही रहती है।

—हरीश तिवारी

कायापलट का साल : १९८७ ने जैसे दोनों ी कायापलट कर दी। असफलताओं, तनाव और केलेपन से संघर्ष कर रही डिंपल फिल्म 'इंसानियत दुश्मन' और 'इंसाफ' की सफलता के बाद सुपर टार बन गयी, दूसरी तरफ डिपल को "मैं उसे अनलकी' कैसे मान सकता हूं, आखिर वह मेरे च्चों की मां भी तो है" कहनेवाले राजेश खन्ना अनलकी' ग्रहों के फेर में फंस गये। एक तरफ उनकी फल्में (रामअवतार, अवाम, अलग-अलग आदि) री तरह से बाक्स आफिस पर पिटीं, तो दूसरी रफ तनाव और असफलता के इन्हीं क्षणों में टीना नीम भी उन्हें छोड़ गयी। "मेरी जिंदगी में अब डपल का कोई काम नहीं, वह हमेशा के लिए निकल यी है" कहनेवाले राजेश खन्ना ने बड़े धैर्य से टीना यथार्थ को भी स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ डपल अकसर यह कहती रही, "आज भी मैं बीवी नने को तैयार हूं, लेकिन पहले जैसी भावुकतापूर्ण र्खता नहीं करूंगी, बल्कि सोच-समझ कर कदम ठाऊंगी ..." लेकिन 'किसकी बीवी, राजेश खन्ना ा किसी और की?' जैसे सवाल हंस कर टाल ती रही।

फिल्मों की असफलता, राजनीतिक वफलता और 'इंपा' (फिल्म निर्माताओं की स्था— इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसियेशन) के नाव में मिली उनकी टीम की पराजय तथा टीना नीम की बेवफाई ने राजेश खन्ना को निपट अकेला र दिया। कुंठा के दौरे से गुजरते हुए राजेश खन्ना फर से अपने आपको व्यस्त रखने के लिए फिल्म-र्माण की योजना में जुट गये। यों इसके पहले टीना लिए बनायी उनकी फिल्म—'अलग-अलग' बुरी रह से फ्लाप हो चुकी थी। उनके एक पार्टनर उनसे लग होकर ड़िपल को बतौर नायिका लेकर एक फल्म बनाने में जुट गये थे।

इसी दौरान एस० चंद्रशेखर से उनकी लाकात हुई, जो अपनी एक तमिल हिट फिल्म के हदी री-मेक के लिए सही फिल्म निर्माता की तलाश थे। तीन नायकोंवाली इस सुपर हिट फिल्म के र्माण-अधिकार राजेश खन्ना ने खरीद लिये और र्देशन की जिम्मेदारी एस० चंद्रशेखर पर ही सौंप ी। फ़िल्म का नाम रखा गया 'जय शिव शंकर'। ाजेश खन्ना अभिनीत जे० ओमप्रकाश की सुपर हट फिल्म 'आपकी कसम' का एक गाना 'जय जय शवशंकर, कांटा लगे ना कंकर' राजेश खन्ना को ाफी पसंद था। इत्तिफाक से 'आपकी कसम' भी ापत्य जीवन के टकराव-अलगाव की दुखांत फिल्म ी, जिससे वह गुजर चुके थे। बस इस फिल्म का ाम 'अमर अकबर अंथोनी' की तर्ज पर 'जय शिव ंकर' रख दिया। जय की भूमिका अपने पास रख र शिव की भूमिका के लिए जीतेंद्र तथा शंकर के लिए चंकी पांडे को अनुबंधित कर लिया। अभी तक ाजेश खन्ना बहुसितारीय (कई नायकों वाली) ल्मों में काम करने से परहेज करते रहे, लेकिन स फिल्म से उन्होंने अपनी यह कसम भी तोड़ दी।

राजेश और डिंपल को साथ लेकर फिल्म नाने की कोशिश बहुत से जाने-माने फिल्मकार र चुके थे, लेकिन आपसी मतभेद के बर्फ को तोड़ने में असफल रहे। यों डिंपल हर बार कहती रही कि अगर उसे राजेश खन्ना के साथ कोई फिल्म मिलेगी, तो वह जरूर करेगी, लेकिन फिल्म की कहानी सुनकर। लेकिन उन्हें कोई साथ नहीं ला सका, और अंतत यह सेहरा बंधा उन्हीं की दोनों बेटियों—ट्विंकल और चिंकी के सिर।

एक होने की चाह ? : डिंपल और राजेश खन्ना

जब राजेश खन्ना के कट्टर विरोधी महेश भट्ट राजेश खन्ना की ही जिंदगी को मद्देनजर रखकर उनकी परित्यक्ता पत्नी डिंपल कपाड़िया को असली डिंपल की भूमिका देकर 'काश' फिल्म बना रहे थे, तो उन्हें संभवतः सपने में भी आभास नहीं रहा होगा और न डिंपल को यह अहसास हुआ होगा कि 'काश' की यह सिचुएशन वर्ष भर के भीतर ही हकीकत बन जायेगी। यों हमेशा भट्ट ने राजेश खन्ना के लिए खुला आफर रखा था कि वह चाहें तो 'काश' में डिंपल के पति की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए न तो डिंपल ही राजी हुई न राजेश खन्ना ही।

> **दांपत्य सूत्र में पुनः बंधने की संभावना को दोनों ऊपरी तौर पर यह कहते हुए नकारते हैं कि फिल्म में साथ काम करने का यह मतलब नहीं कि हम फिर से पति-पत्नी की तरह रहने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से डिंपल राजेश को 'अपनी बच्चियों के पिता के रूप में' तथा राजेश डिंपल को 'अपनी बच्चियों की मां के रूप में' इज्जत देने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि दोनों पुनः शादी कर लेंगे।**

अपूर्व मिलन : दोनों को मिलाने का काम किया वयः संधि में पैर रख रही डिंपल-राजेश की बेटी ट्विंकल ने। अपने जन्मदिन पर उसने दोनों को सात समदर पार नैरोबी में एकत्र किया, एक ही होटल में, भले ही अलग-अलग कमरों में सही, दोनों को ठहरने के लिए बाध्य किया। काफी समय दिया-दोनों को एकांत में एक-दूसरे से बात करने के लिए। डिंपल को मानसिक रूप से तैयार किया कि वह खुद आगे बढ़कर पापा की फिल्म की हीरोइन की भूमिका मांगे और उसे लेने की जिद्द करे। दूसरी तरफ राजेश खन्ना की हिचक को तोड़ने और अनुराधा पटेल को साइन कर लेने के बावजूद उस रोल को डिंपल को सौंपने के लिए ट्विंकल और चिंकी ने पापा को विवश किया और सफल रहीं। इसके पहले भी वे अपने जन्मदिन पर मम्मी-पापा को एक साथ एकत्र करती थीं और छुट्टियों में ज़ब भी स्कूल से बंबई आतीं, डिंपल को साथ लेकर ही डैडी से मिलने 'आशीर्वाद' जातीं। राजेश खन्ना सारा काम छोड़कर दोनों बेटियों के बीच जब तक गप्पें हांकते, तब तक डिंपल बंगले का मुआयना करती, नौकरों से बातचीत करती या टेलीफोन पर 'बिजिनेस टाक' करती। शूटिंग होती तो वह बच्चियों को राजेश खन्ना के पास छोड़ कर स्टूडियो चली जाती और शाम को स्टूडियो से सीधे जाकर वापस ले आती।

राजेश खन्ना की फिल्म 'जय शिव शंकर' के लिए डिंपल ने अपनी अधिकांश डेट्स राजेश खन्ना को, उनकी इच्छानुसार दे दी हैं। उसने 'माया' को बतलाया, "मेरी दोनों बेटियों की ख्वाहिश थी कि मैं उनके पापा के साथ एक फ़िल्म में काम करूं। अपनी बच्चियों का दिल न तोड़ने और उनकी जिद्द पूरी करने का मौका जब मेरे हाथ आया, तो मैंने उसे जाने नहीं दिया।"

दांपत्य सूत्र में पुनः बंधने की संभावना को दोनों ऊपरी तौर पर यह कहते हुए नकारते हैं कि फिल्म में साथ काम करने का यह मतलब नहीं कि हम फिर से पति-पत्नी की तरह रहने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से डिंपल राजेश को 'अपनी बच्चियों के पिता के रूप में' तथा राजेश डिंपल को 'अपनी बच्चियों की मां के रूप में' इज्जत देने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि दोनों पुनः शादी कर लेंगे शादी की बात चलते ही राजेश खन्ना बड़े फख्र से कहते हैं, "शादी? अरे हमारे बीच तलाक हुआ ही कहां, जो पुनः शादी कर लेंगे। कानूनन अभी भी हम मियां-बीवी हैं, फिर दुबारा शादी करने का सवाल ही कहां उठता है?" डिंपल 'दुबारा शादी' की कोई व्याख्या नहीं करती और मुस्करा कर खामोश रह जाती है। "अगर कोई निर्माता-निर्देशक चाहेगा कि उसकी फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम करूं, तो जरूर करूंगी, लेकिन कहानी और रोल पहले मैं फाइनल करूंगी।" वह 'माया' को बतलाती है।

पता नहीं, यह 'फाइनलाइजेशन' डिंपल या राजेश करेंगे या फिर उनकी दोनों बेटियां ही उन्हें कार्टर रोड स्थित बंगले 'आशीर्वाद' में वापस ले आयेंगी, जिसका अभी पुनः नवीनीकरण चल रहा है और कुछ महीने में एक भव्य बंगला बनकर तैयार हो जायेगा।

—हरीश तिवारी, बंबई ब्यूरो

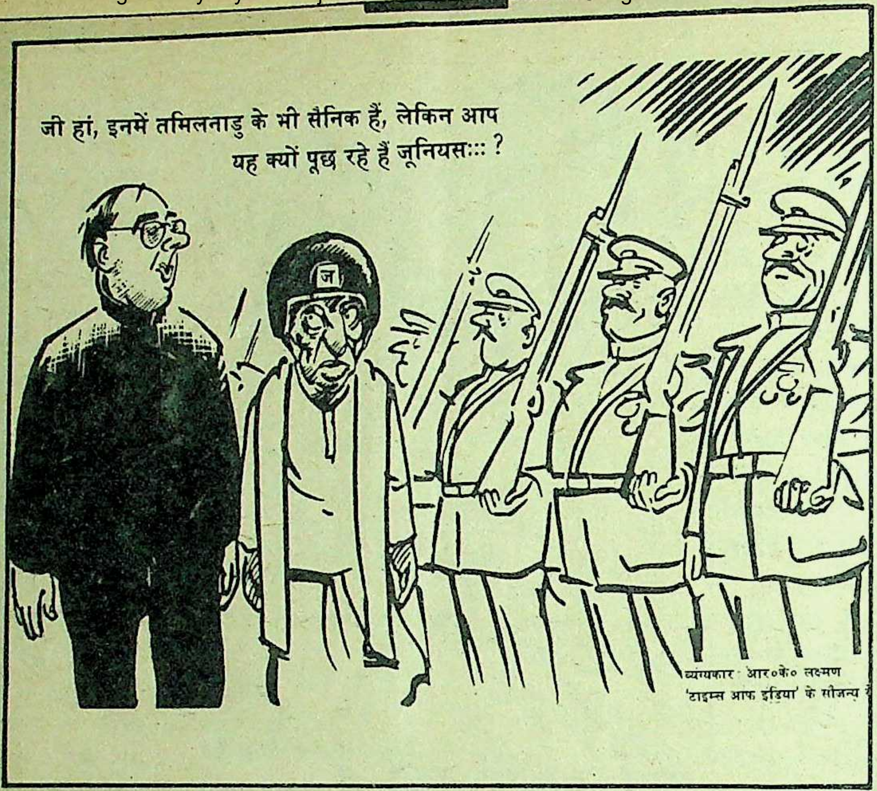
जी हां, इनमें तमिलनाडु के भी सैनिक हैं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं जूनियस::: ?
ज

व्यंग्यकार आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य से

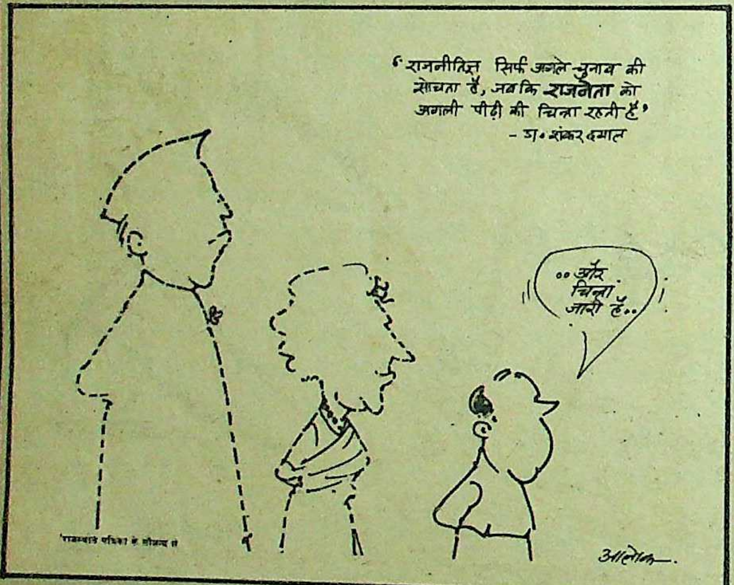
'राजनीतिज्ञ सिर्फ अगले चुनाव की सोचता है, जबकि राजनेता को अगली पीढ़ी की चिन्ता रहती है' - डा० शंकर दयाल
..और चिन्ता जारी है..
आलोक

'राजस्थान पत्रिका' के सौजन्य से

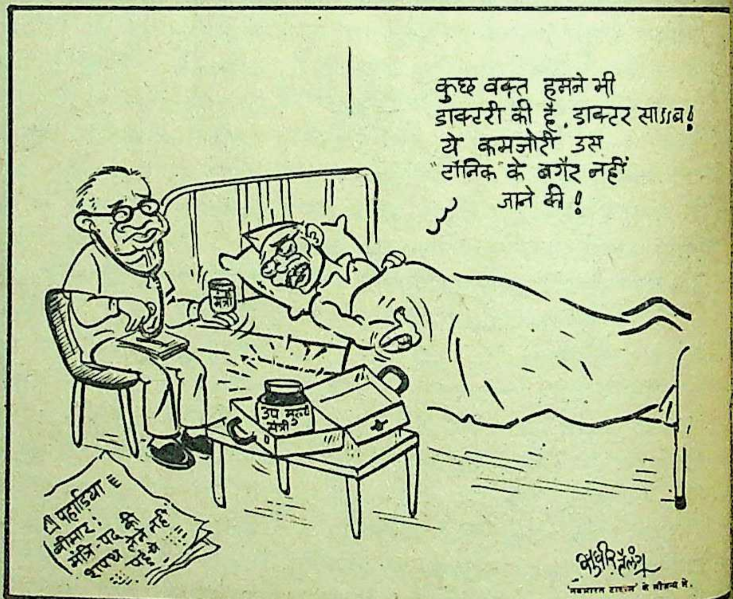
कुछ वक्त हमने भी डाक्टरी की है, डाक्टर साऽऽब! ये कमजोरी उस 'टॉनिक' के बगैर नहीं जाने की!
मंत्री
उप मुख्य मंत्री
पहाड़िया बीमार: मंत्रि-पद की शपथ
सुधीर तैलंग

'नवभारत टाइम्स' के सौजन्य से.

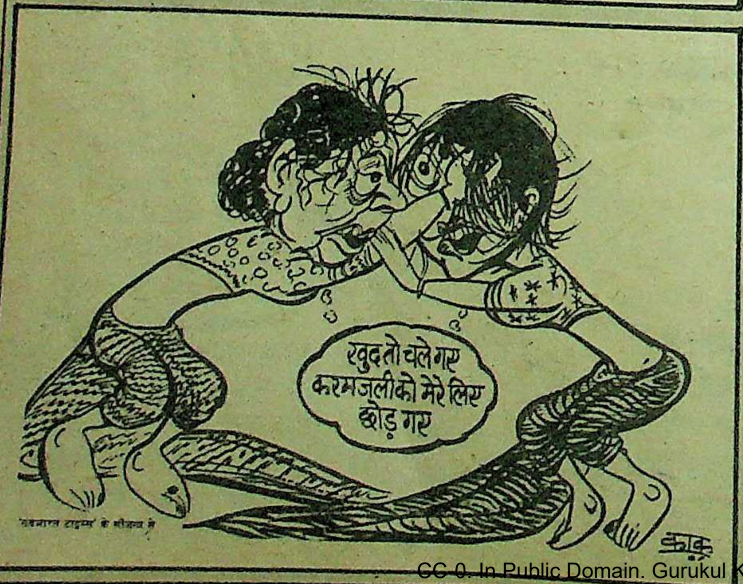
खुद तो चले गए करमजली को मेरे लिए छोड़ गए
काक

'नवभारत टाइम्स' के सौजन्य से

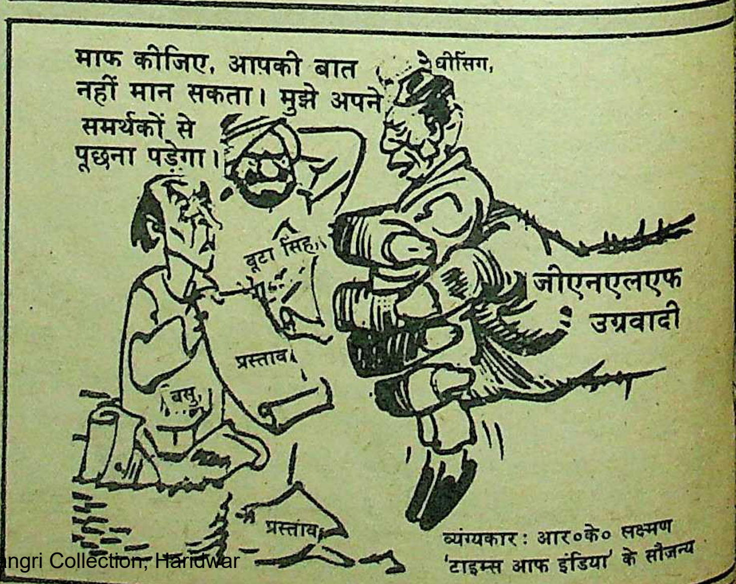
माफ कीजिए, आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे अपने समर्थकों से पूछना पड़ेगा।
घीसिंग,
बूटा सिंह
प्रस्ताव
बसु
प्रस्ताव
जीएनएलएफ उग्रवादी

व्यंग्यकार: आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य

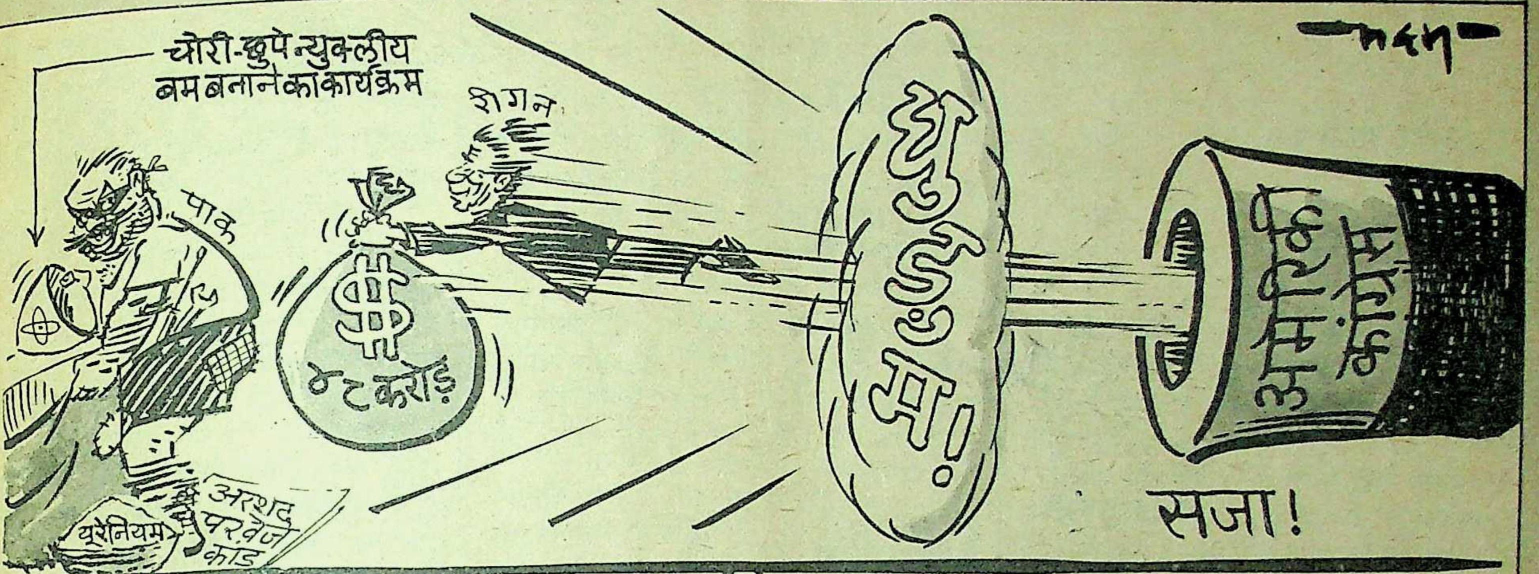
मदन
चोरी-छुपे न्युक्लीय बम बनाने का कार्यक्रम
रीगन
पाक
$
४८ करोड़
यूरेनियम
अरशद परवेज कांड
धुड़ुम!
अमरीकी कांग्रेस

सजा!

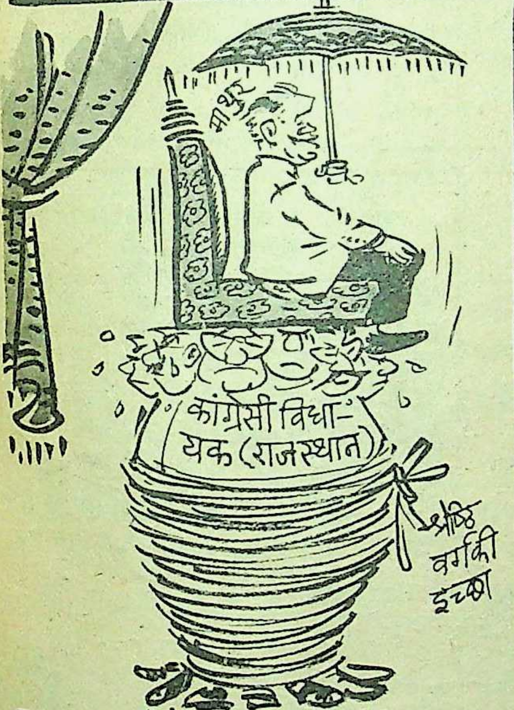
माथुर
कांग्रेसी विधायक (राजस्थान)
श्रेष्ठ वर्ग की इच्छा

राजस्थान में नया मंत्रि मंडल बना –

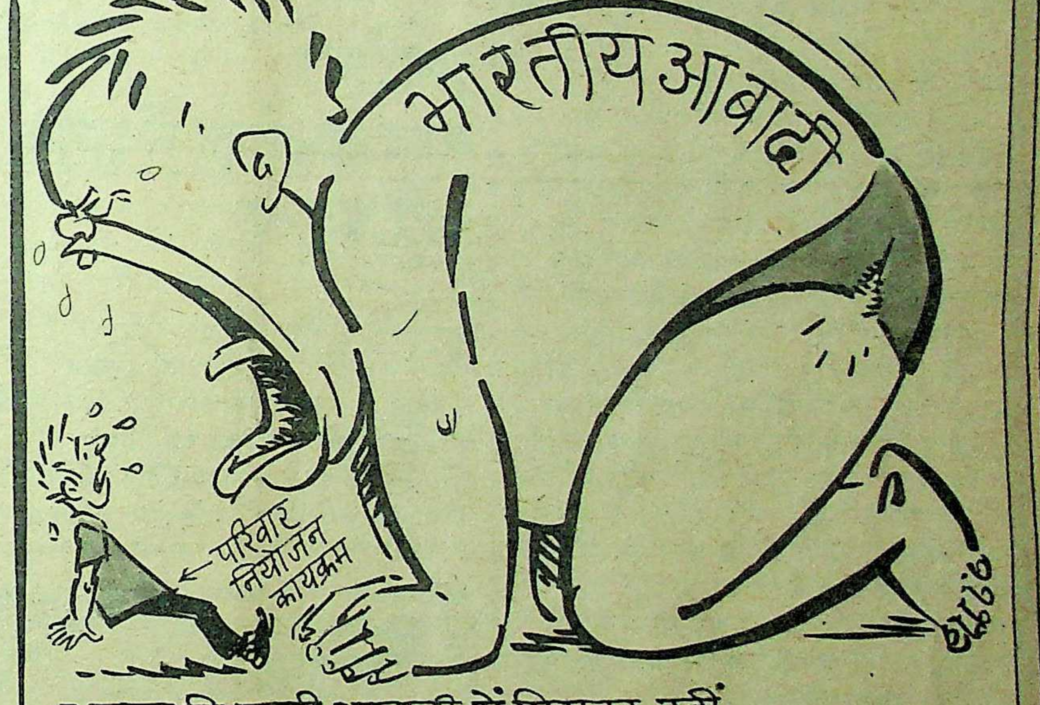
भारतीय आबादी
परिवार नियोजन कार्यक्रम
काक

भारत की बढ़ती आबादी में गिरावट नहीं – समाचार

तेल, लोहा, चीनी, कोयला और पेट्रोल के मूल्यों में केंद्र द्वारा वृद्धि की घोषणा –

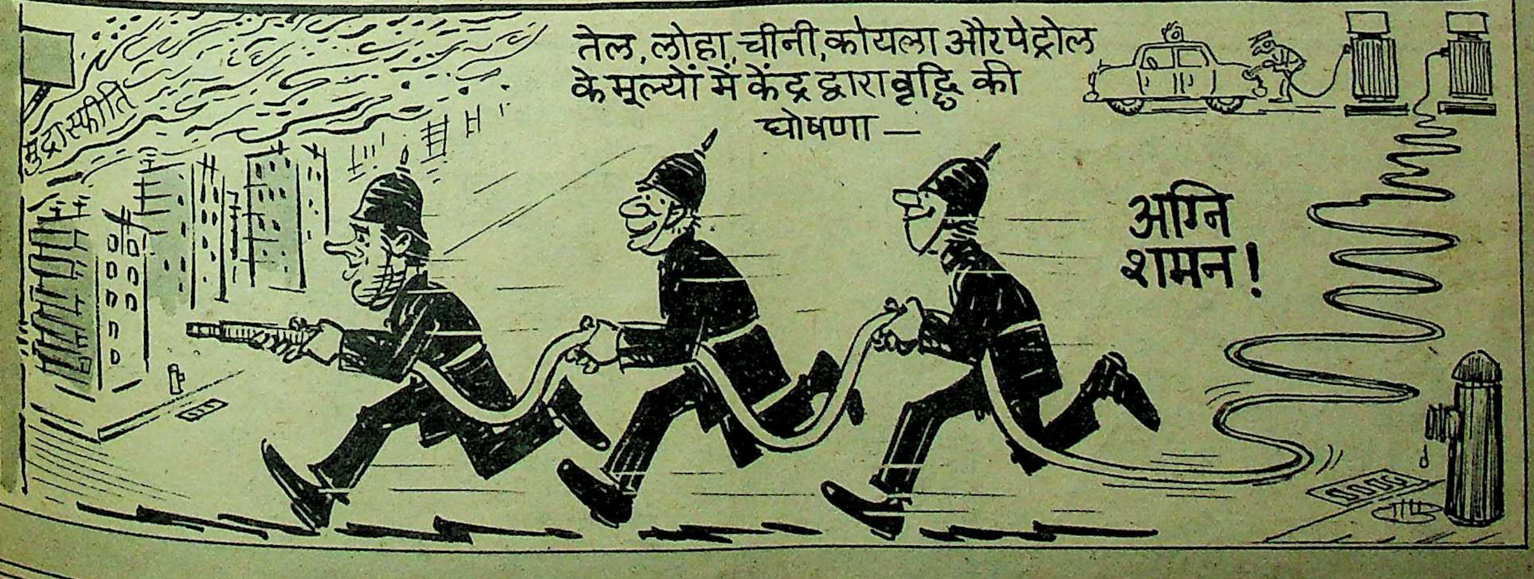
मुद्रास्फीति
अग्नि शमन!

स्टाकहोम सम्मेलन

बढ़ता प्रभाव

दिल्ली बैठक के दौरान छह राष्ट्रों (स्वीडन, भारत, अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूनान और तंजानिया) के इस संगठन की 'परमाणु शस्त्र रहित विश्व' की गुहार को नक्कारखाने में तूती की आवाज कहा गया था, लेकिन अब इसका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब यह और अधिक मुखर बन रहा है। स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में संपन्न हुआ सम्मेलन इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास समझा जायेगा।

स्टाकहोम सम्मेलन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। 'स्टाकहोम घोषणा' में सबसे प्रमुख वह प्रस्ताव रहा जिसमें संयुक्त राष्ट्र से अपील की गयी है कि परमाणु परीक्षणों की जांच करने के लिए एक बहुपक्षीय संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि निरस्त्रीकरण का मसला किन्हीं दो-तीन देशों से संबंधित नहीं है, इसलिए इस मसले में अन्य देशों की भागेदारी भी बढ़नी चाहिए। इस प्रस्तावित बहुपक्षीय संयुक्त समिति में छह राष्ट्रों ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात भी कही है। इन राष्ट्रों का मानना है कि परमाणु परीक्षणों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम साबित होगा। इस घोषणा का मास्को ने स्वागत किया है, जबकि अमरीका ने अभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।

इंग्वर कार्लसन (स्वीडन), राजीव गांधी (भारत), राउल अलफांसिन (अर्जेंटीना), जूलियस न्येरेरे (तंजानिया), आंद्रियास पापेन्द्रु (यूनान) और मिगुएल डिला मैड्रिड (मैक्सिको) द्वारा हस्ताक्षरित इस नौ सूत्रीय घोषणा में यों तो हाल में संपन्न हुए मध्यम दूरी के समझौते का स्वागत किया गया, मगर इसे अपर्याप्त कहा गया है। घोषणा में कहा गया है कि इस समझौते से परमाणु शस्त्रों की बहुत कम मात्रा नष्ट होगी और ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन को भी इसमें शामिल होना चाहिए। संभावित लंबी दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों में पचास प्रतिशत की कटौती का समझौता इसी साल के मध्य तक कर लेने की मांग की गयी है।

प्रस्ताव की दूसरी महत्वपूर्ण बात है अमरीका के 'स्टार वार कार्यक्रम' का विरोध। घोषणा में यह सख्त शब्दों में कहा गया है कि किसी भी हालत में अंतरिक्ष मे परमाणु शस्त्रों की तैनाती को रोका जाना चाहिए, अन्यथा परमाणु शस्त्रों की दौड़ को रोकना फिर असंभव सा हो जायेगा।

छह राष्ट्रों के नेताओं ने इसी साल गर्मियों में न्यूयार्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में फिर मिलना तय किया है। वहां ये इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से इनके प्रयास का दबाव दोनों महाशक्तियों पर भी पड़ेगा।

सम्मेलन की समाप्ति पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यूनान के राष्ट्रपति आन्द्रियास पापेन्द्रु द्वारा दिये गये वक्तव्य से लगता है कि छह राष्ट्रों का अगला सम्मेलन एथेंस में १९८९ की जनवरी में होगा।

निकारागुआ

अमरीका मध्य अमरीका में शांति नहीं चाहता

शांति के नोबल पुरस्कार विजेता कोस्टारिका के राष्ट्रपति आस्कर एरिसाय ने अमरीका को चेतावनी दी है कि वह कोंत्रा-छापामारों को मदद देकर निकारागुआ को हराने में कामयाब नहीं होगा। साथ ही कोंत्रा को उसके द्वारा मिलने वाले एक डालर के जवाब में रूस निकारागुआ को पांच डालर देगा, जिससे मध्य अमरीका में कभी भी
बहाल नहीं हो पायेगी।

लगभग ३२ लाख की आबादी वाला निकारागुआ मध्य अमरीका में स्थित है। निकारागुआ के उत्तर में होंडुरास और द कोस्टारिका है, जबकि पूर्व में कैरेबियन सा और पश्चिम में प्रशांत महासागर है।

१५ जनवरी को कोस्टारिका में पां मध्य अमरीकी देशों (कोस्टारिका, निकार अल सल्वाडोर, ग्वाटेभाला और होंडुरास) बीच दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस सम्मेलन को, म को लागू करने की दिशा में 'अंतिम प्रयास रूप में देखा जा रहा था। बहरहाल, सम्मे काफी अच्छे नतीजे निकले हैं और आशा है कि 'समझौता' निरर्थक नहीं होगा, बश अमरीका टांग न अड़ाये।

पिछले साल सात अगस्त को मध्य अमरीकी देशों ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते को बाद में काफी महत्वपूर्ण आंका गया और समझौते मसौदा तैयार करनेवाले आस्कर एरियास नोबल पुरस्कार भी इसी पर मिला। अम ने इस समझौते का कभी भी खुले दिल से स्वागत नहीं किया और एरियास को नोब पुरस्कार दिये जाने पर भी उसने नाक-भौं सिकोड़ी थी। इस भय से कि कहीं उस पर शांति प्रयासों को भंग करने का आरोप न जाये, उसने थोड़े दिन तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन कोंत्रा-छापामारों को अपनी मदद शुरू कर दी।

सम्मेलन में निकारागुआ के राष्ट्रप डेनियल ओर्तेगा पर काफी दबाव पड़ रहा

इन्हें अपने ही देश के खिलाफ लड़ा रहा है अमरीका: कोंत्रा छापामार

CC-0. In Pub

कि समझौते के मुताबिक वह जरूरी कदम उठायें। ओर्तेगा ने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वायदे के अनुसार मार्च १९८२ से लागू इमरजेंसी उठा ली गयी। विशेष अदालतें समाप्त कर दी गयीं। कोत्रा-छापामारों से सीधी बातचीत भी शुरू हो गयी है। एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी है कि समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जायेगा, यदि अमरीका या अन्य देश उन्हें अपनाने को तैयार हो जायें। कोंत्रा-छापामारों से भी आम माफी की पेशकश की गयी है। उधर अमरीका ने भी ३० दिन के लिए कोंत्रा-छापामारों को दी जाने वाली मदद रोक ली है। चुनांचे कांग्रेस ने छापामारों को देने के लिए एक

ध्य अमरीका में शांति चाहते हैं: डेनियल ओर्तेगा

ड़ी रकम को स्वीकृति दे दी और रीगन-शासन और धन प्राप्त करने की कोशिश है।

दरअसल, राष्ट्रपति ओर्तेगा और उनकी डिनिस्टा पार्टी से अमरीका की दुश्मनी काफी रानी है। जिया, मार्कोस, दुबालिये, चुन दू ान आदि तानाशाहों को समर्थन देने की उसकी ति रही है। निकारागुआ में लगभग दस साल हले सिमोजा नामक तानाशाह का राज था। मोजा वंश काफी समय से (१९३३-१९७९) हां राज करता आ रहा था। दूसरी तरफ शनल लिबरेशन फ्रंट तानाशाही से मुक्ति के ए संघर्ष कर रहा था। हर स्रोत से ताना-ह सरकार द्वारा जनता के दमन के समाचार रहे थे, मगर जिमी कार्टर (अमरीका) रकार आंख मूंद कर अपना समर्थन सिमोजा दिये जा रही थी। एक दिन एन०बी०सी० नेशनल ब्राडकास्टिंग कंपनी) के एक पत्रकार संकेत देने के बावजूद सिमोजा की सेना ने र डाला, मगर उसके पीछे आ रहे उसके थियों ने उस घटना की फिल्म बना ली और रीका में दिखा भी दी। इसके बाद काफी बावेला मचा। जब कार्टर सरकार की जमकर थू-थू होने लगी, तो उन्होंने सिमोजा को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया। आखिरकार १९७९ में सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सिमोजा का तख्ता पलट दिया। सिमोजा ने सपरिवार भागकर पेरुग्वे में शरण ली, जहां बाद में उसकी हत्या हो गयी।

१९८४ के आम चुनाव में ओर्तेगा के नेतृत्व में सैंडिनिस्टा पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। ओर्तेगा ने देश में समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किये जो अमरीकी सरकार को जंचे नही, चुनांचे ओर्तेगा सरकार को उलटने की कोशिशें शुरू हो गयीं। सी०आई०ए० एजेंट निकारागुआ पहुंचने लगे। सिमोजा समर्थक निकारागुआ नेशनल गार्ड (सोमोस्तन) ने अमरीका के इशारे पर पड़ोसी देश होंडुरास में शरण ली। इन कोंत्रा-विद्रोहियों को अमरीका ने सैनिक साजो-सामान और प्रशिक्षण देकर निकारागुआ के खिलाफ लड़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने ईरान गेट कांड तक कर डाला। इधर निकारागुआ को भी क्यूबा और रूस से मदद मिलने लगी। समस्या दिनोदिन गंभीर होती गयी। अमरीका अपने इरादों में कामयाब तो नहीं हुआ मगर मध्य अमरीका की स्थिति बिगड़ती गयी। मध्य अमरीका शांति समझौते से राजनीतिक समाधान की आशा बंधी थी, लेकिन अमरीकी नीति के चलते यह भी अभी तक अधर में लटकी है।

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

तस्करी अब प० जर्मनी से भी

पश्चिमी जर्मनी की एक कंपनी 'न्यूकेम' द्वारा पाकिस्तान और लीबिया को परमाणु सामग्री सप्लाई करने के भंडाफोड़ के बाद यह बात खुलकर सामने आ गयी है कि पाक को गुपचुप परमाणु बम बनाने में अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों का न केवल समर्थन हासिल है, बल्कि वह उसे हर तरह से सहयोग भी दे रहे हैं।

इस भंडाफोड़ के अनुसार पश्चिमी जर्मनी की 'न्यूकेम' कंपनी बेल्जियम की एक प्रयोगशाला को परिष्कृत यूरेनियम सप्लाई करती थी, जहां से यह पाकिस्तान और लीबिया को भेजी जाती थी। पश्चिमी जर्मनी के कानून के मुताबिक किसी भी ऐसे देश को परमाणु सामग्री नहीं दी जा सकती, जिस पर परमाणु बम बनाने का शक हो। जानकारी मिलने के तुरंत बाद कंपनी में ताला लग गया और जांच बिठा दी गयी है। इसी तरह हालैंड और ब्रिटेन द्वारा ४५ किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम पाकिस्तान भेजे जाने की भी खबर है।

इस घटना के बाद यह संदेह और पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के प्रयास में जोर-शोर से जुटा हुआ है और इसके लिए जरूरी सामग्री प्राप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकानेवाली बात यह है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को कुछ पश्चिमी देशों का सहयोग मिल रहा है। अमरीका के समर्थन की पुष्टि तभी हो गयी थी जब पिछले साल पाकिस्तानी मूल के कनाडावासी अरशद परवेज को अमरीका से परमाणु सामग्री की तस्करी करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। अमरीकी अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद भी रीगन प्रशासन ने नियमों में फेरबदल करके पाकिस्तान को चार अरब डालर से ज्यादा की मदद जारी कर दी थी।

अरशद परवेज के मामले को अमरीका ने जिस तरह लिया था, उसी से पता चल गया था कि पाक परमाणु कार्यक्रम को उसका मौन समर्थन हासिल है। लेकिन इस नये मामले से पता चला है कि पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम और हालैंड भी गुपचुप तरीके से उसे इसमें सहयोग कर रहे हैं।

इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के अलावा एक और खबर ऐसी है जिससे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संदेह मजबूत होता है। खबर है कि पाकिस्तान जल्दी ही एक और परमाणु संयंत्र लगाने की कोशिश में है। इस संयंत्र में यूरेनियम को परिष्कृत करने की व्यवस्था होगी जो कि परमाणु बम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है।

सवाल यह उठता है कि अमरीका सहित कई पश्चिमी देश एक तरफ तो भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आखिर उनकी इस दोहरी नीति का क्या अर्थ है? क्या वह भारत की घेरेबंदी में जुटे हैं? या फिर परमाणु बम का हौआ खड़ा करके भारत को अपने स्वार्थों के लिए झुकाना चाहते हैं?

—मुकेश कुमार

भगत सिंह गिल

जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकेंड का फासला हो, सभी असहाय हो गये हों और ऐसे में मौत का फासला तय करने के पूर्व कोई साहसी व्यक्ति किसी को जिंदगी बख्श दे, तो ऐसे साहसी का कोई सानी नहीं हो सकता। जिंदगी देने वाला वह व्यक्ति उस परिवार के लिए भगवान-सरीखा हो जाता है। पर ऐसा साहसी व्यक्ति भगत सिंह गिल सिर्फ इसे अपना कर्तव्य समझता है।

१६ जनवरी को पुरानी दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर ३ से एक सात वर्षीय लड़की प्रगति फिसलकर रेलवे लाइन पर गिर पड़ी। उसी समय गंगा-यमुना एक्सप्रेस ट्रेन उसी रेलवे लाइन पर आ रही थी। ट्रेन और प्रगति के बीच कुछ ही क्षणों का फासला था कि दिल्ली पुलिस के सब-इंसपेक्टर ५६ वर्षीय भगत सिंह गिल ने छलांग मारी और प्रगति को मौत के मुंह से बचा लिया। ट्रेन गुजर गयी। हादसा टल गया। श्री गिल प्रगति को लिये एक ओर खड़े थे। इस साहसपूर्ण करतब को कर्तव्य माननेवाले श्री गिल का कहना है कि उनकी जान भी जा सकती थी, पर उस समय सोचने का वक्त नहीं था, कर्तव्य ललकार रहा था और बच्ची को गिरते देखकर ही मैंने छलांग लगायी। यदि मै यह सब सोचने लग जाता, तो बच्ची ट्रेन के नीचे आ जाती।

हो सकता है कोई और साहसी व्यक्ति होता, तो अपने इस साहस का ढिंढोरा पीटता और साहस के लिए पुरस्कृत होना चाहता, पर पंजाब के रोपड़ जिले के झलयांकला गांव के बाशिंदे श्री गिल कर्तव्य पूरा करके खामोश हो गये। उन्होंने अपने अधिकारियों तथा परिवार के सदस्यों तक को कुछ नहीं बताया। उनका मानना है कि बच्ची की जिंदगी बच गयी, यही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।

अरविंद सिंह

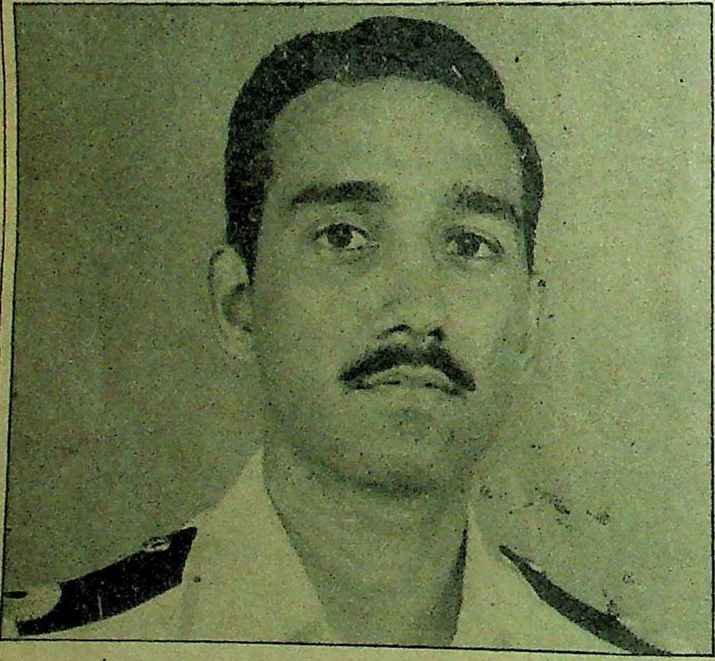

इस बार महावीर चक्र का सम्मान मिला है, भारतीय नौसेना के ले० अरविंद सिंह को। उन्हें यह सम्मान श्रीलंका में लिट्टे छापामारों से युद्ध में अपूर्व साहस का परिचय देने पर मिला है। गोलाबारी के बीच अपनी जान की परवाह किये बिना अरविंद सिंह ने अपने जवानों को लेकर लिट्टे छापामारों द्वारा बिछायी गयी बारूदी सुरंगों को सफलतापूर्वक हटाने का अदम्य साहस दिखाया था। लखनऊ में जन्में अरविंद सिंह ने बचपन से ही देश-सेवा करने का मन बना लिया था। सेंट फ्रांसिस कालेज, ला मार्टीनियर कालेज और लखनऊ विश्वविद्यालय से (बी०एस०सी०) शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह १९८० में नौसेना में भरती हुए। उन्होंने मेधाविपन, लगन और देश-सेवा के संकल्प के चलते नौसेना में एक अफसर और एक सैनिक-दोनों रूपों में बहुत कुछ प्राप्त किया। गहरे समुद्र में गोताखोरी का प्रशिक्षण, काम्बैट, पैरा जंपिंग, मैरीन कमांडों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ अरविंद सिंह ने अमरीका में विशेष युद्धकला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस और अपूर्व कार्यों की बदौलत उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैडेट का सम्मान (स्वर्ण पदक) राष्ट्रपति के हाथों से मिला।

अपने भाइयों में सबसे छोटे अरविंद सिंह अपने व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे प्रेरणास्रोत के रूप में अपने पिता डा० वी०एस० चौधरी का नाम लेते हैं। उनका मानना है कि देश-सेवा के संकल्प को पुख्ता करने में पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। सैनिक जीवन के ८ वर्षों में ही महावीर चक्र विजेता होना इस बात का प्रमाण है कि अरविंद सिंह में देश-प्रेम कूट-कूट कर भरा है और वह हर पल साहस दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे विजेता पर हर देशवासी को नाज है।

कांग सू यान

दक्षिण कोरिया की कांग सू
की खुशी का ठिकाना न र
जब उसके मित्र ने उसे बताया
कि उसे ४४वें वेनिस अंतरा
फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए
चुना गया है। कुछ देर तक
मित्र का मुंह वह आश्चर्य से
देखती रही कि वह सच बोल
है या झूठ, लेकिन फिर उसे
ही यकीन आ गया और उसने
अपने मित्र को चूम लिया।

२१ वर्षीय कांग को फि
'सीवाजी' (सरोगेट वूमेन) में
उसके शानदार अभिनय के लि
विश्व में फिल्म जगत का स
ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान दिया
गया है। इस फिल्म में उसने
ऐसी दुखी महिला की भूमिका
निबाही है, जिसको एक धनी
के पुत्र की आकांक्षा पूरी करने
वाली 'किराये की मां' बनना
पड़ता है। इस फिल्म का निर्दे
इम कोंतेक ने किया है।

वैसे कांग दक्षिण कोरि
टी०वी० कलाकार के रूप में
ही काफी मशहूर है। उसने क
टेली नाटकों में बच्चों की भूमि
निभायी हैं।

अपनी इस महत्वपूर्ण
उपलब्धि का श्रेय वह अपने
निर्देशक और प्रोडक्शन स्टाफ
देती है। निर्देशक इम इस
उपलब्धि से दूसरी बार चर्चा
आये हैं। इसके पहले १९८६ में
शिकागो फिल्म समारोह में उ
फिल्म 'गिल्सोडम' को विश्व
सम्मान से पुरस्कृत किया गया
था।

—दिनेश

मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,

DUPLICATE

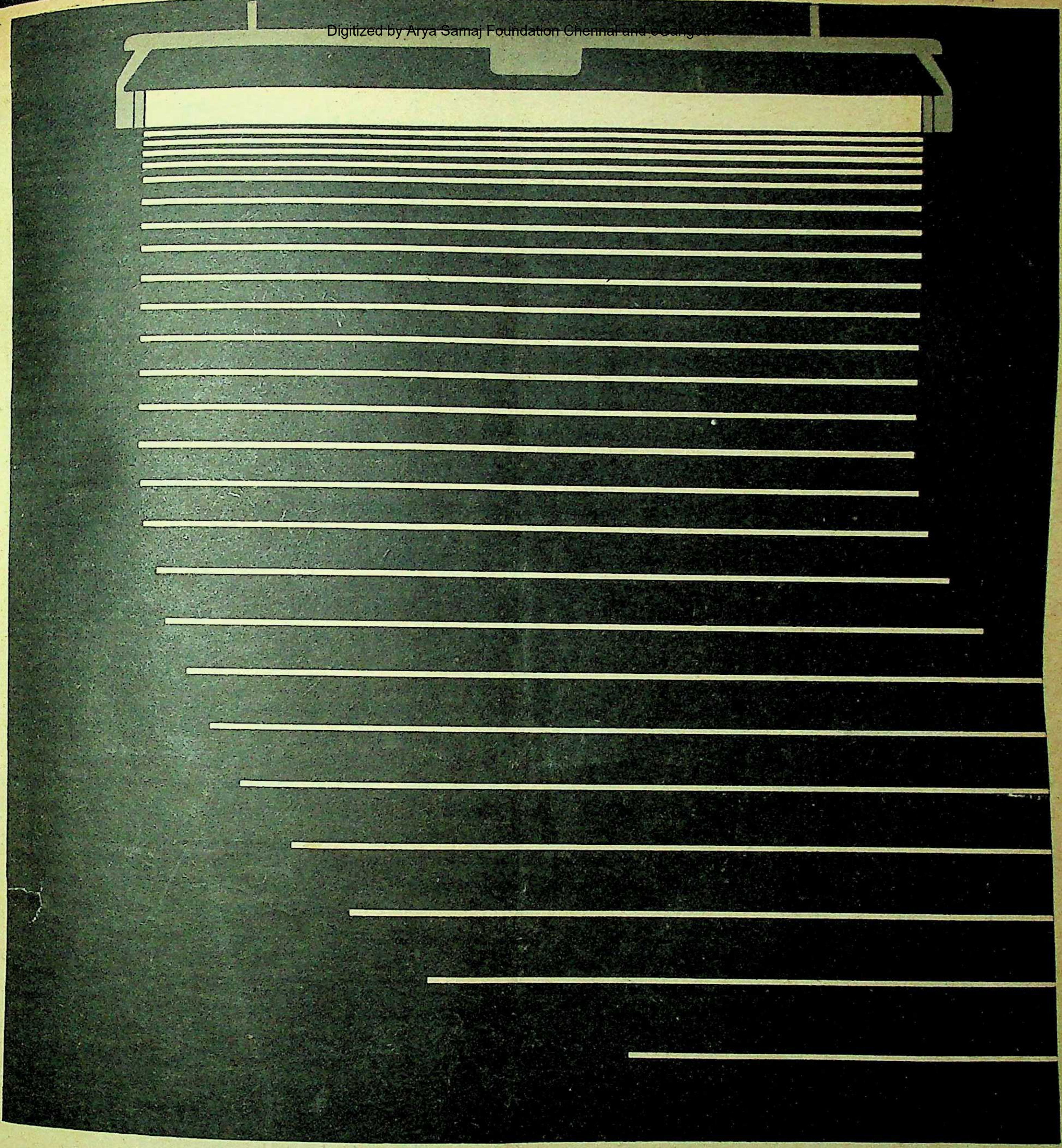

बजाज 'सिल्वरलाइट' पट्टी में किफ़ायती 'बेलास्ट' और सही किस्म का अन्य सामान लगे होने के कारण यह फ़्लोरोसेंट ट्यूब को भरपूर कुशलता से काम करने में सहायता देती है. ताकि आपको बिजली का खर्च कम आए और रोशनी ज़्यादा मिले.

बजाज 'सिल्वरलाइट' पट्टी और बजाज फ़्लोरोसेंट ट्यूब की जोड़ी बेजोड़ है. और किफ़ायती भी. बरसों तक बगैर तकलीफ़ के काम देती है.

7/3/88
पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

bajaj group

बजाज पट्टी और ट्यूब

bajaj

सही रोशनी के लिए सही जोड़ी

Heros/BE-874 HN

अपनी आय बढ़ाइए
– आयकर नहीं

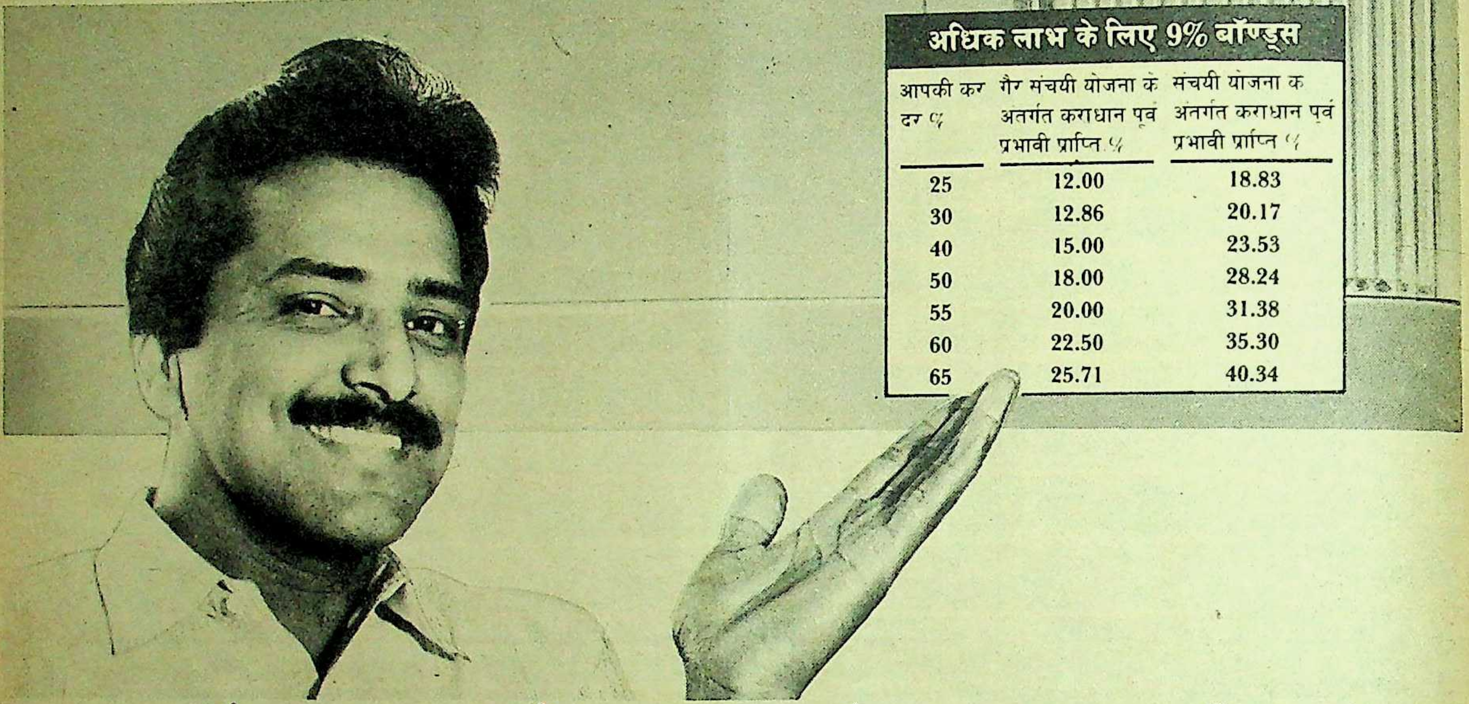

अधिक लाभ के लिए 9% बॉण्ड्स

आपकी कर दर %	गैर संचयी योजना के अन्तर्गत कराधान पूर्व प्रभावी प्राप्ति %	संचयी योजना के अन्तर्गत कराधान पूर्व प्रभावी प्राप्ति %
25	12.00	18.83
30	12.86	20.17
40	15.00	23.53
50	18.00	28.24
55	20.00	31.38
60	22.50	35.30
65	25.71	40.34

9% (कर-मुक्त) व 13% (कर छूट सहित)
एन.टी.पी.सी. पावर बॉण्ड्स

9% (कर-मुक्त) बॉण्ड्स

- सभी करदाताओं के लिए ब्याज बिना सीमा के आयकर मुक्त
- संचयी योजना के अन्तर्गत कुल ब्याज रु. 1412/- वार्षिक प्राप्ति दर 14.12%
- आबंटन तिथि के तीन वर्ष बाद छोटे निवेशकों से सममूल्य पर वापस क्रय की सुविधा
- **10 वर्ष** बाद सममूल्य पर विमोचन

साथ ही पेश हैं – 13% बॉण्ड्स

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80L के अन्तर्गत ब्याज कर-मुक्त
- संचयी योजना के अन्तर्गत कुल ब्याज रु. 1415/- वार्षिक प्राप्ति दर 20.21%
- आबंटन तिथि के एक वर्ष बाद छोटे निवेशकों से सममूल्य पर वापस क्रय की सुविधा
- **7 वर्ष** बाद सममूल्य पर विमोचन

और अनेक समान विशेषताएं

- निवेश पूर्णतया सम्पत्ति कर से मुक्त
- स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं
- खैराती एवं धार्मिक निधियों को आयकर में विशेष लाभ
- ब्याज की दो योजनाएं: संचयी एवं गैर-संचयी
- संचयी योजना के अन्तर्गत ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा
- गैर-संचयी योजना के अन्तर्गत बॉण्ड्स के साथ ही छमाही, उत्तर-दिनांकित ब्याज वारंट पेशगी भेजे जाएंगे जिनका स्वतः ही निर्धारित तिथि पर भुगतान लिया जा सकता है
- आवेदन पत्र के साथ प्राप्त धन की वसूली की तारीख ही ब्याज देय
- पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा आसानी से हस्तान्तरणीय
- हस्तांतरण स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त
- देश के 7 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों की सूची में दर्ज
- कंपनी की सम्पत्तियों द्वारा पूर्णतया सुरक्षित
- बोली गारंटियों/बयाना एवं जमानत के तौर पर एन.टी.पी.सी. द्वारा स्वीकार्य

40,00,000 सिक्योर रिडिमेबल, रु. 1000 प्रत्येक के 9% (कर-मुक्त) एवं 13% बॉण्ड्स का सममूल्य पर सार्वजनिक निर्गम – कुल राशि रु. 400 करोड़

निर्गम आरम्भ : 10 मार्च 1988
निर्गम समाप्ति : 19 मार्च 1988

निर्गम के प्रबंधक

एस. बी. आई
कैपिटल
मार्केट्स
लिमिटेड
202, मेकर टावर्स 'ई'
20वीं मंजिल, कफ परेड
बम्बई-400 005

कैनबैंक
फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
1-ई, बन्दना बिल्डिंग, टॉलस्टाय मार्ग
नई दिल्ली-110 001.

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन लि.
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एन.टी.पी.सी स्क्वायर,
62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

Sobhagya/42/88/H

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक ५

१५ मार्च, १९८८

माया

यह अंक

आवरण कथा

माया
राज्यों और
केंद्र में फेरबदल
किस लिए?

३०

राजीव गांधी ने रातोरात मध्य प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री बदले हैं और झटपट अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। इन परिवर्तनों में प्रधानमंत्री ने इतनी हड़बड़ी क्यों बरती? मुख्यमंत्रियों को चुनने और केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के लिए उन्होंने क्या आधार बनाया? इन परिवर्तनों के पीछे राजीव गांधी का मकसद क्या है और क्या उनका वह मकसद पूरा हो सकेगा?

हरियाणा

भाई-भतीजावाद के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री देवीलाल के राज का जायजा और उनसे बेबाक भेटवार्ता : ७४

आंध्र प्रदेश

इंका के चौतरफा हमले से घिरे एन०टी० रामाराव का कहना है कि इंका उन्हें ब्लैकमेल करने पर तुली है, उनसे विशेष साक्षात्कार १६

राजस्थान

मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते ही शिवचरण माथुर किस संकट में फंस गये हैं? ६३

पंजाब

आतंकवाद से निपटने में सरकार क्यों असफल रही, इसका जवाब दे रहे हैं, पंजाब-राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे। ८६

मध्य प्रदेश

क्या अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बन कर आने पर चुरहट लाटरी-कांड फिर से गरमायेगा? ५८

जिलाधिकारी

प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिलाधिकारियों से मुलाकात करने की क्या जरूरत पड़ गयी? २५

दिल्ली दरबार : रीशफल का खेल ६
फोटोफीचर ९
बेढब १३
अभिमत : भीष्म साहनी : राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या १४
खोजखबर : कोयला उद्योग चौपट २१
अपराध : डा० बासु घोष : हत्या या आत्महत्या? ४७
उत्तर प्रदेश : सूखा राहत की रकम कहां गयी? ५०
बिहार : किस्सा बिहार भवन का ५३
राजस्थान : डाक्टरों का राजरोग ६९
अर्थतंत्र : सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ८९
तथ्य-कथ्य ९२
परदे के पीछे ९४
खेल : वेंगसरकर को सजा किसलिए? ९६
दूरदर्शन : नेता से अभिनेता ९८
विदेश १०३

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५६६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया
तमस सीरियल पर विवाद क्यों?
इलाहाबाद लोकसभा सीट
राजीव की इज्जत

हरिजन किधर जायेंगे ?

१५ फरवरी '८८ के अंक में प्रकाशित लेख 'हरिजन किधर जायेंगे ?' वास्तव में विचारणीय है। 'माया' द्वारा समाज के उन वर्गों के लिए सही प्रश्न उठाया जाना, जिन्हें हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, स्वच्छ पत्रकारिता की दिशा में एक जागरूक प्रयास है। इसमें दो मत नहीं कि कांग्रेस ने अब तक के हरिजन नेताओं को केवल शो पीस की तरह रखा है।विपक्षी हरिजन नेताओं को कांग्रेस खरीदती आयी है, लेकिन यह युग बाबू जगजीवन राम का नहीं रामविलास पासवान का युग है, जो अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने नेतृत्व के लिए स्वयं सक्षम है।

वर्तमान समय में हरिजनों का कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो पूरे राष्ट्र में स्थापित हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब एक लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न दलित नेतृत्व एकजुट होकर साबित करेंगे कि दलित क्या हैं ? हरेक दलित को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। उसे भगवानवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्म और जातिवाद के विरुद्ध अपना मोर्चा संभाल लेना चाहिए।

'माया' द्वारा आगे भी हम इसी प्रकार के विचारोत्तेजक विषय उठाने की अपेक्षा करते हैं। स्वच्छ एवं प्रशंसनीय विचारधाराओं के लिए हार्दिक बधाई ! **—बासुदेव, बस्ती सौंदा, हजारीबाग, झारखण्ड**

हरिजन भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं। वे पहले भी शोषित थे और आज भी शोषण के शिकार हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आजादी के चार दशक बीत जाने के बाद भी हम हरिजनों के साथ जुड़े दलित और शोषित शब्द को नहीं हटा सके। इसका प्रमुख कारण हमारी राजनीतिक दुरावस्था है और वे तथाकथित हरिजन नेता जो दलित और शोषित शब्द पर गर्व करते हैं और उन्हें सही नेतृत्व नहीं दे पाते हैं। हरिजनों के शोषित होने का प्रमुख कारण उनकी अशिक्षा है। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। आरक्षण (जिसका लाभ सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित है) उन्हें और अधिक पंगु बना रहा है। अतः हरिजनों का शिक्षा की ओर रुझान होना आवश्यक है, साथ ही हरिजन नेतृत्व का दंभ भरने वालों को भी चाहिए कि वे अपने समाज के लोगों को जागृत करें, उन्हें भीख लेना नहीं, अपना अधिकार मांगना सिखायें। अन्यथा हरिजन-सवर्ण खाई फैलती रहेगी और राजनेता अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। **—संजय चतुर्वेदी, पातरा परी घाट, भोपाल, मध्य प्रदेश**

यह लेख पढ़कर सचमुच ही लगने लगा है कि कांग्रेस ही नहीं अपितु हर दल हरिजनों को 'वोट बैंक' समझने लग गया है। इसका परिणाम वही सामने आता है, जैसाकि हाल ही में पाण्डातराई (म०प्र०) में हुआ। दरअसल, पिछले वर्ष नवंबर में करमाराम द्वारा गठित दलितों के संघ 'भारतीय शोषित दल' को भारतीय शासित दल कहा जाये, तो कोई उज्र नहीं होगा। अगर समय रहते इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वर्ग भी भूमिगत उग्रवादी संगठनों व नक्सलवाद की ओर अग्रसर न हो जायें। **—मदन सिंह पंवार, अमलाबे, राजगढ़ (ब्यावरा), मध्य प्रदेश**

इंका संगठन क्या फिर से जिंदा हो पायेगा ?

'इंका संगठन : क्या फिर से जिंदा हो पायेगा ?' (१५ फरवरी '८८) पढ़ा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली कांग्रेस की संगठन प्रक्रिया को देखा जाये, तो एक बात स्पष्ट रूप से दिखायी देती है कि यह नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की नहीं। सत्ता के साथ संबद्ध हो जाने के सपने ने कांग्रेस में भीड़ को बढ़ाया है। हर व्यक्ति ने कांग्रेस में कभी धन, कभी जाति, तो कभी जुटायी गयी भीड़ के माध्यम से शक्ति-प्रदर्शन कर टिकट पाने की चेष्टा की। प्रदेश स्तर पर [illegible] गुट सक्रिय रहे। असंतुष्टों को कुरसी देकर संतुष्ट करने का प्रयास चलता रहा, फिर भी टांगखींचू प्रवृति को नहीं रोका जा सका। संगठन में भी दर्जनों प्रकोष्ठों का प्रावधान कर कई अध्यक्षों, कई उपाध्यक्षों व कई पदों के निर्माण कर एक गलत परंपरा डाली गयी, क्योंकि इन प्रकोष्ठों का कार्य कुछ नहीं होता। अतः कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की निष्ठा कुरसी रही, न कि पार्टी व संगठन। कांग्रेस उनके लिए धंधे का माध्यम बन गयी, न कि मिशन। संगठन के फिर से जिंदा हो जाने की बात काफी जटिल प्रक्रिया है। **—ज्ञानेश चौबे आजादगंज, हरदा**

इंका संगठन संभालने के लिए इंका अध्यक्ष को पुराने कांग्रेसियों को खुश करना पड़ेगा और अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। पिछले अंक में विद्याचरण शुक्ल ने साक्षात्कार में कहा था कि बजट से पूर्व कोई मुख्यमंत्री जायेगा और हरिदेव जोशी चले भी गये, इसी को रोकना होगा। अपनी मा से सत्ता पा लेने के बाद राजीव गांधी हर मिशन पर फेल हुए हैं। राजीव गांधी की पार्टी पर पकड़ ढीली पड़ गयी है, इसलिए वह जल्दी-जल्दी महासचिव बदलते रहते हैं। **—अदनान अब्बासी, निजामपुर, गोरखपुर**

बढ़ती जनसंख्या घटता उत्पादन

'माया' १५ फरवरी के अंक में 'बढ़ती जनसंख्या घटता उत्पादन' के अंतर्गत देश में कृषि उद्योग की वास्तविकता को उजागर किया गया है। देश में कृषि का उत्पादन गिरता जा रहा है, जबकि यह देश का प्रमुख एवं आवश्यक उद्योग है। शिक्षा प्रणाली भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा की बहुत कमी है। सरकार न तो कृषि के साधन बढ़ाती है और न ही कृषि की शिक्षा की ओर ध्यान देती है। खेती से जुड़ा आम आदमी हायर सेकेंड्री तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाता है और यह शिक्षा उसे कोई दिशा नहीं देती। वह नौकरी की तलाश में यहां-वहां भटक कर अपना समय और पैसा भी बर्बाद करता है। असफल होकर अनमने ढंग से खेती करता है, उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त होंती। इस तरह वह अपना जीवन बर्बाद करता है। **—विजय सिंह, जबलपुर**

दो महिलाओं का सत्ता संघर्ष

'माया' के १५ फरवरी वाले अंक की आवरण कथा 'दो महिलाओं का

'तमस का उजाला

'माया' के फरवरी द्वितीय अंक में 'तमस' पर बेहतरीन रपट पढ़ी। यदि इसमें कमेंट्री के अलावा विश्लेषण पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता, तो रचना अद्वितीय बन सकती थी। धारावाहिक के विभिन्न पेंचों का खुलासा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। ''तमस' के अलावा जिन दो कहानियों का उपयोग इस धारावाहिक में किया गया है, उनका जिक्र भी नदारद है।

यदि कथा की भूमिका को ही ढंग से समझ लिया जाये, तो दंगों की पूरी वजहों का जानना मुश्किल नहीं होगा। पूंजीपरस्त राजनीति में ही सांप्रदायिकता फलती-फूलती है। इसे हम अपने आसपास झांककर समझ सकते हैं। इसी राजनीतिक व्यवस्था में आरएसएस, शिवसेना, आदम सेना आदि पनपती हैं और चूंकि यही व्यवस्था अंग्रेजों के समय भी थी, इसलिए मुस्लिम लीग, हिंदू परिषद आदि पनपे, जिसका नतीजा था विभाजन के समय भड़की हिंसा। अब ये सांप्रदायिक संगठन गांव-गांव में पहुंच गये हैं और सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी-तैसी करने में लगे हैं। मेरा गांव केवल दस हजार आबादी वाला है। यहां कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती भाग गयी। दोनों में पहले से ही संबंध थे, मगर दोनों जाति के कट्टर संगठनों ने ऐसी हवा बनायी कि दंगा होने की नौबत आ गयी। लेकिन 'तमस' का फायदा अब साफ नजर आ रहा है। लोग सांप्रदायिक ताकतों को पहचानने लगे हैं और कुछ हद तक उनसे दूरी भी बनाने लगे हैं।

भाजपा जैसे कट्टरपंथी दलों का विरोध नाजायज है। दरअसल, इनकी दिक्कत यह है कि इनका अतीत खोलकर सामने रख दिया गया है जोकि वास्तव में इनका वर्तमान भी है। बहरहाल, यह देश के हित में अच्छा ही हुआ है कि 'तमस' जारी रहा और कट्टरपंथी ताकतों को हार का मुंह देखना पड़ा।

—तरुण अवस्थी, बुढ़ार, मध्य प्रदेश

सत्ता संघर्ष' पढ़ा। इसमें तमिलनाडु के हीरो स्व० एम०जी० रामचंद्रन की वास्तविक छवि प्रस्तुत की गयी। लोगों के हृदय में राज करने वाले रामचंद्रन की राजनीति वास्तव में हमेशा से जनता को मूर्ख बनाती रही थी। 'माया ने रामचंद्रन की उत्कृष्ट चारित्रिक जानकारी दी है। जिससे यह सिद्ध होता है कि वह दो नावों में सवारी करने वाले व्यक्ति थे जो आवश्यकतानुसार किसी एक को अपंना लेते थे या दोनों को मझधार में छोड़कर स्वयं किनारे लग जाते थे। यह स्वयं उनके लिए तथा जनता के लिए खतरनाक बात थी।

आदतन उन्होंने अपने अंतिम समय में भी यही किया। दोनों को मझधार में छोड़कर स्वयं किनारे लग गये। अर्थात मरने के बाद स्वयं तो शांत हो गये, किंतु पूरे तमिलनाडु को अशांत कर गये। खासकर उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने पत्नी तथा प्रेमिका को ही आपस में उलझा दिया है। और अंत में मैं यह कहूंगा कि रामचंद्रन को 'भारत-रत्न' की उपाधि देकर राजीव गांधी ने उस पुरस्कार की विश्वसनीयता खो दी है। राजीव गांधी के किसी भी निर्णय को लोग भविष्य में आशका की दृष्टि से देखेंगे। **—सुदेश देशमुख, कोरबा**

मुठभेड़ की असलियत

'माया' के १५ फरवरी के अंक में 'मुठभेड़ की असलियत' पढ़कर ऐसा लगा जैसे आज भी हमारे देश में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। राजू भटनागर का अंत सुनिश्चित था, किंतु सवाल राजू भटनागर जैसे क्रूर अपराधी के दुखद अंत का नहीं है। प्रश्न तो यह उठता है कि इस तरह के अपराध एवं अपराधी को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है? इस सवाल का सटीक उत्तर है, हमारे द्वारा चुने गये, राजनीतिज्ञ एवं भ्रष्ट अफसर! राजू भटनागर चाहे किसी की भी गोली का निशाना बना हो, सारे-के-सारे पुलिस दल को इसका श्रेय देना उचित होगा न कि किसी एक अफसर को।' **—रामनरेश मिश्रा 'विद्यार्थी', बरगद, कटनी**

मराठा और दलितों के बदलते तेवर

'माया' के फरवरी प्रथम अंक में 'मराठा और दलितों के बदलते हुए तेवर' के आसार पढ़कर ऐसा लगा कि 'रिडिल्स आफ हिंदुइज्म' के चौथे खण्ड का विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि उक्त पुस्तक एक हरिजन द्वारा लिखी हुई है। प्रो० भास्कर राव जाधव से लेकर गोपाल राव देशमुख तक ने हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध काफी कुछ लिखा, यहां तक कि शिव सेना के प्रमुख बाल ठाकरे के पिता प्रबोधंकर ठाकरे ने भी हिंदू धर्म के विरुद्ध काफी कुछ लिखा, लेकिन तब इतना बावेला क्यों नहीं मचा? डाक्टर अंबेदकर जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, अगर उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर कर दिया है, तो इसका विरोध क्यों? भारत की प्राचीन संस्कृति से लेकर आधुनिक संस्कृति तक के बारे में बोलने का अधिकार सभी वर्गों और संप्रदायों को है। इस अधिकार से कोई वंचित नहीं है। यह अधिकार डा० अंबेदकर को भी था, हरिजन होने से यह अधिकार घट नहीं गया। **—मोतीलाल राम, मंझौल, बेगूसराय**

क्या कभी ऐसा कंप्यूटर भी बनेगा?

१५ फरवरी '८८ का 'माया' अंक पढ़ा। योजना आयोग का 'लाईडिटेक्टर' और जानवरों की लग्न-पत्री बनाने वाले कंप्यूटरों के निर्माण की बात पढ़कर हर्ष हुआ और प्रश्न भी मन में उठा कि क्या वैज्ञानिक ऐसे कंप्यूटर नहीं बना सकते जो 'फेयर फैक्स' और 'बोफोर्स' ऐसे मामलों की छानबीन बिना 'संसदीय समिति' के ही कर सकें? क्या ऐसे कप्यूटर नहीं बनाये जा सकते जो न्यायाधीशों को अपराधियों को जानने के लिए मदद कर सकें? पुलिस को भी इनसे मदद मिलती है। वास्तव में यदि इस प्रकार के कंप्यूटर बन जाते, तो देश का कायाकल्प हो जाता और घरों में ताले नहीं लगते। **—त्रिलोकीनाथ यादव, प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री उ०मा० विद्यालय, मुसहा, बस्ती**

खेद है

'माया' २६ फरवरी, १६८८ अंक में पृष्ठ ५० पर प्रकाशित बाक्स 'सिर मुंडाते ही ओले' के अंतर्गत लिखा गया है कि श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर को अपनी पुत्री के बाल विवाह के आरोप में मंत्रिमंडल से निकाला गया था। वास्तव में उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। यह आरोप एक अन्य मंत्री पर लगा था।

—सं०

जिस प्रकार अंग्रेजों ने पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का मसला जानकर छोड़ा ताकि वे लड़ते रहें और हमारी शक्ति पर निर्भर करें। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ तथा अन्य स्थानों के झगड़े उलझाये रखे ताकि फैसले उन पर निर्भर हों और बिल्लियों के झगड़ों में बंदर की तरह वे सत्ता की रोटी खा सकें। **—'दिनमान' में दर्शन सिंह रागी**

प्रधानमंत्री की आंखें हैं, पर देखती नहीं, कान हैं, पर सुनते नहीं और मुंह है, जो बोलता नहीं। **—किसान आंदोलन के प्रति राजीव गांधी की उपेक्षा पर बहुगुणा की टिप्पणी, 'जनसत्ता' में**

जो हम गत चालीस वर्षों में प्राप्त नहीं कर सके, वह चालीस दिनों में पाकर दिखायेंगे। **—महेंद्र सिंह टिकैत**

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, उसका महत्व अखबारों के लिए हो सकता है, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व नहीं है। **—'टाइम्स', लंदन**

मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री द्वारा हेर-फेर किये जाने से ही लगता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार अस्थिर है। **—ज्योति बसु, 'स्टेट्समैन' में**

मेरी सरकार बिहार में स्वच्छ प्रशासन के लिए कटिबद्ध है। **—बिहार के नये मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, 'इंडियन एक्सप्रेस' में**

अब मैं लोगों के बीच जाकर काम करूंगा। **—मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफे के बाद हरिदेव जोशी, 'इंडिया टुडे' में**

हो सकता है कि ज्योति बसु मार्क्सवाद के ज्ञाता हों, लेकिन यह सत्य है कि वह आतंकवाद नहीं समझते। **—सुभाष घीसिंग, 'टेलीग्राफ' में**

डंका अपने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटकर आम समस्याओं की ओर से लोगों का ध्यान हटा रही है। **—देवीलाल**

कर्पूरी ठाकुर कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना जीवन पिछड़े वर्गों के उद्धार और सामाजिक विषमताएं दूर करने में अर्पित कर दिया। उनके निधन से देश और बिहार ने प्रमुख राजनेता खो दिया है। **—राजीव गांधी**

मेरठ आकर लगा कि टिकैत कितनी बड़ी शख्सीयत का नाम है। इस आंदोलन को देखकर लगा कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गयी होगी। **—राजबब्बर, 'चौथी दुनिया' में**

यह टीम के लिए अच्छी बात नहीं है कि कोई खिलाड़ी इस तरह टीम से बाहर कर दिया जाये। **—दिलीप वेंगसरकर के खेल पर पाबंदी लगने पर कपिलदेव की प्रतिक्रिया।**

हमारा यह मेल फिलहाल पूरी तरह से व्यावसायिक मेल है। फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर हम करीब आते चले गये और वह 'आशीर्वाद' में वापस आ गयी, तो इसे मैं निश्चय ही तकदीर का खेल और कुदरत का करिश्मा समझूंगा। **—राजेश खन्ना, 'माधुरी' में**

दर्शन सिंह रागी

देवीलाल

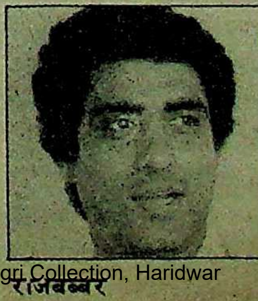

राजबब्बर

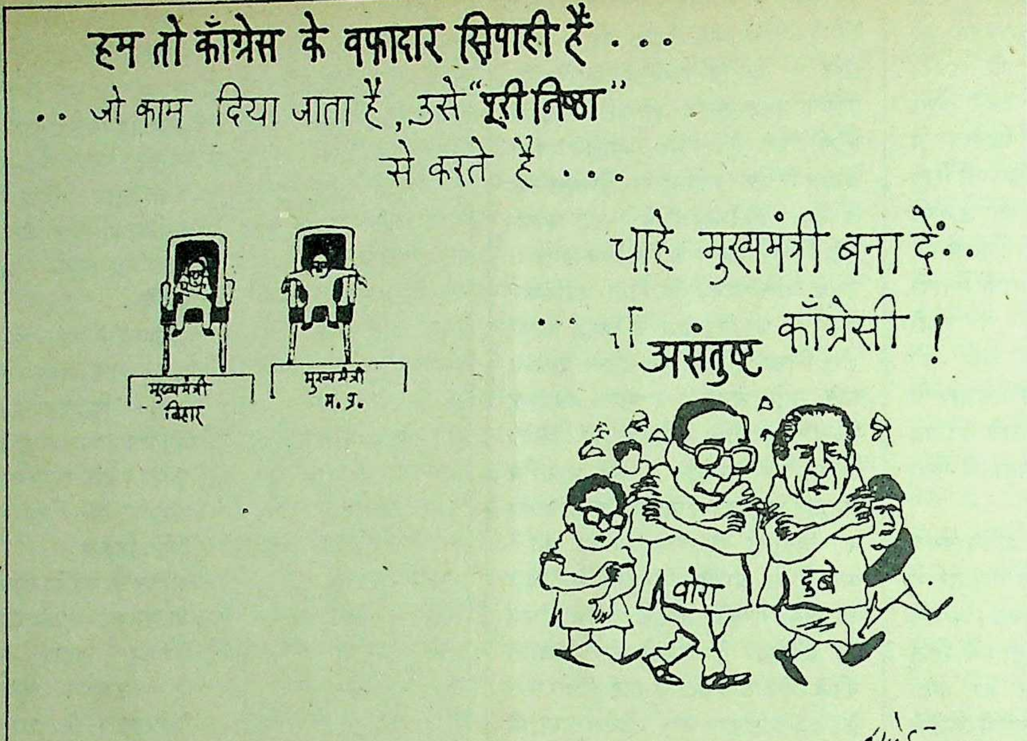
हम तो काँग्रेस के वफादार सिपाही हैं . . .
. . जो काम दिया जाता है, उसे "पूरी निष्ठा" से करते हैं . . .
मुख्यमंत्री बिहार
मुख्यमंत्री म. प्र.
चाहे मुख्यमंत्री बना दें . .
. . . या असंतुष्ट काँग्रेसी !
वोरा
दुबे

रीशफल का खेल

आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली दरबार की राजकाज चलाने की ट्रेनिंग 'एशियाड' में हुई थी। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान हुआ क्या कि वह खेल-एडिक्ट हो गये। अब लत-तो-लत ही है, छूटती तो है नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे खेल की ईजाद की जाये, जिससे खेल की तलब भी पूरी हो जाये और जो नायाब भी हो। आउटडोर खेल में सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए वह खेल इनडोर होना चाहिए। दिल्ली दरबार देखते ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें एक आइडिया दिखा और मस्त होकर झूमने लगे। उनको दिखायी पड़ा कि उन्हें 'रीशफल-रीशफल' खेल खेलना चाहिए। यह इनडोर भी है और मजेदार भी। बस फिर क्या था, हो गये शुरू। तब से वह हर दो महीने में एक बार यह खेल खेल ही लेते हैं।

पहले उनके इस खेल में कई जोड़ीदार हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नये-नये अंतरंग बने बूटा सिंह को ही खेल-साथी बनाया। यह किसी से नहीं छुपा है कि बूटा सिंहजी खेल मंत्रालय में खेल चुके हैं और अपने गृह मंत्रालय को भी वह खेल के अलावा कुछ नहीं समझते। अब देखिए न जब से उन्होंने अपनी बेनाप की अचकन की थैले-सी जेब में गृह मंत्रालय को डाला है, तब से सारे देश में 'अमन चैन' है। अब पंजाब में अगर रोजाना लोग मारे जाते हैं, तो वह क्या करें? घोड़ा घास से यारी करेगा, तो खायेगा क्या? अगर पंजाब में शांति हो गयी, तो फिर अपने बूटा भाई को पूछेगा ही कौन? बूटा सिंह की जान को आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं। लेकिन यदि पंजाब में शांति हो गयी, तो फिर बूटा भाई की राजनीतिक हत्या सुनिश्चित है। इसलिए वह निर्दोष पंजाबियों की हत्याएं रोक कर अपनी हत्या क्यों करवायें?

अपने दिल्ली दरबार को बूटा सिंह पर बड़ा नाज है। वह मानते हैं कि नेहरूजी के पास सरदार पटेल जैसे नामी-गिरामी गृहमंत्री थे जरूर, लेकिन वह नाम के सरदार थे, जबकि अपने बूटा सिंह असली सरदार हैं। ना-नुकुर भी नहीं करते और जी-हुजूरी में भी अव्वल।

अपनी-अपनी पसंद है। अब दिल्ली दरबार को बूटा सिंह पसंद हैं, तो हैं—कोई क्या कर लेगा? इसलिए उन्होंने इस बार 'रीशफल-रीशफल' खेल में इकलौते बूटा सिंह को ही साथ लिया।

दिल्ली दरबार ने बूटा सिंह से कहा, "सरदारजी बताइये खेल कहां से शुरू करें?" बूटा सिंह ने अपनी अचकन के निचले बटन खोले, पगड़ी को ठीक किया और बोले, "हुजूर पहले हमें 'डाज' देना चाहिए।" दिल्ली दरबार आश्चर्य के साथ बोले, "क्या मतलब?" "आप समझे नहीं, हमको पहले मुख्यमंत्री बदलने की बात करनी चाहिए। लोगबागों का ध्यान उसमें लगा रहेगा और हम चुपचाप केंद्रीय मंत्रिमंडल की ताशों को फेंट लेंगे। आप तो जानते हैं, इन कांग्रेसियों को। ये न राम के हैं, न रहीम के। ये तो सत्ता के पुजारी हैं। अगर इनको पता लग गया कि सत्ता बंटने का काम हो रहा है, तो ये मारे अपने-अपने गुट लेकर आप पर पिल पड़ेंगे और आपकी आफत आ जायेगी। इसलिए आप 'डाज' दीजिए और चुपचाप मुख्यमंत्रियों के बदलने की बात करके केंद्रीय मंत्रिमंडल की लाटरी खोल दीजिए। आपकी धाक जम जायेगी। लोग समझ जायेंगे कि पार्टी में आप ही 'सुप्रीम' हैं। आप चाहे जिसको जो बना देते हैं और पार्टी सिर झुका कर मान लेती है। अखबारवाले लिखेंगे, अब दिल्ली दरबार बालिग हो गये, वह किसी की सलाह के मोहताज नहीं, अपने दिमाग से काम लेने लग गये हैं।"

बूटा सिंह की बात सुनकर दिल्ली दरबार की बाछें खिल गयीं। उन्होंने कपिल देव के लहजे में कहा, "बूटा सिंह दा कोई जवाब नहीं।" फिर उन्होंने 'अब हम न्याय करेंगे' के लहजे में कहा, "अब हम 'रीशफल-रीशफल' खेलेंगे।" खेल चालू हो गया। बूटा सिंह ने एक काम की सलाह और दी, "हुजूर आप यह योग्यता का झंझट छोड़िए, आप तो कोटा फिक्स

कर लीजिए। कुछ कोटे बना लीजिए जैसे वीपी सिह कोटा।" दिल्ली दरबार ने ज्योंही वीपी सिह का नाम सुना, उन्हें रामायण सीरियल का दृश्य याद आ गया, वह 'रामायण' के रावणीय लहजे में गरजे, "बूटा सिह तुमने फिर वीपी का नाम लिया।" बूटा सिह ने हंसकर कहा, "आप सुनिए तो सही, मेरा मतलब है वीपी सिह आपकी खाट खड़ी करने के लिए चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, इसलिए पहले आपको इस विभीषण से निपटना है।" दिल्ली दरबार को बात समझ में आ गयी। उन्होंने एक पुराना पत्ता उठाया और देखा दिनेश सिह हैं। बूटा सिह ने कहा, "बिलकुल ठीक। यूपी में तो एक तुरुप मिल गया, लेकिन एम०पी० में भी तो शुक्ला के साथ वीपी ने धावा बोल रखा है।" दिल्ली दरबार ने कहा, "अब बूटा सिहजी आपकी बारी है।" बूटा सिह ने पहले से ही एक पत्ते की पहचान कर रखी थी। उनको मौका मिल गया और उन्होंने उस पत्ते को दिल्ली दरबार के हाथ में थमा दिया। वह तुरुप का इक्का अर्जुन सिह थे। दिल्ली दरबार गद्गद हो गये, "हां, ठीक है। यह बहुत तिकड़मी बनता है। इसे बैक टू पैवेलियन कर देना चाहिए। फिर इसके पास दिल्ली में कोई काम भी नहीं है—केवल टिकट जारी करता था या फिर विदेशों के 'एसटीडी कनेक्शनों' का उद्घाटन करता था।"

दिल्ली दरबार ने सवालिया नजरों के साथ कहा, "हां बूटा भाई अब दूसरे कोटे की बात करिए।" बूटा सिह ने कहा, "अब हमें कांशीराम के कोटे से मंत्री लेने चाहिए।" दिल्ली दरबार को लगा यह बूटा सिह दोस्त है या दुश्मन। इसने अजीब तरह के कोटे बना रखे हैं। लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। बूटा सिह ने कहा अब पत्ता फेंकने की आपकी बारी है। दिल्ली दरबार ने तुड़ा-मुड़ा एक पत्ता फेंका, लेकिन उसके साथ एक पत्ता और चिपका था। बूटा सिह ने कहा, "कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे।" बूटा सिह ने महाबीर प्रसाद और डूमर लाल बैठा को अपने पांव के नीचे दबा लिया।

बूटा सिह ने तीसरा कोटा जगन्नाथ मिश्र और वीसी शुक्ला का बनाया और दिल्ली दरबार की तरफ एक साथ दो पत्ते फेंके, जिनमें एक वोरा का था और दूसरा दुबे का। "हुजूर भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों की वोराजी ने बड़ी 'सेवा' की है, इसलिए इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए और दुबेजी के न्याय के डंके सारे बिहार में बज रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायमंत्री बना दीजिए। दुबेजी की एक खासियत और है। वह केवल बारहवीं पास हैं। अशोक सेन की तरह बात-बात में कानून भी नहीं बघारेंगे।" दिल्ली दरबार को बात समझ में आ गयी।

अब स्वयं दिल्ली दरबार की ओर से सुझाव आया, "बूटा सिहजी शहाबुद्दीन-आरिफ मोहम्मद कोटा कैसा रहेगा?" 'चंगाजी चंगा बादशाहो।' दिल्ली दरबार ने फिर दो पत्ते फेंके। एक जफर शरीफ का और दूसरा रफीक आलम का। इसी बीच दिल्ली दरबार को अचानक गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनायी पड़ी। वह चौंके, "बूटा यह आवाज कैसी?" बूटा सिह ने कहा, "यह हुक्के की आवाज है हुजूर। मेरठ से आ रही है। यह जो टिकैत है न, यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तंबाकू बना कर पी रहा है। इसका कुछ इलाज कीजिए।" दिल्ली दरबार ने कहा, "यह अपना वीरू उस्ताद क्या कर रहा है? वह टिकैत का हुक्का-पानी बंद क्यों नहीं कर पा रहा है?" बूटा सिह ने फरमाया, "हुजूर आप तो जानते ही हैं। वह मुकद्दर का सिकंदर है। पहले वीपी सिह के कारण और अब टिकैत के कारण उसकी कुरसी सही सलामत है। वैसे वीरू उस्ताद का कहना है, "टिकैत के आंदोलन को थका कर मारूंगा। चूं तक नहीं करूंगा। यदि टिकैत गरियार बैल है, तो मैं भी भैंसा हूं। अगर उसके सामने मैं झुक गया, तो फिर वह किसी के वश में नहीं आयेगा।" आप तो जानते ही हैं कि वह 'रैली-एक्सपर्ट' हैं। पहले उन्होंने नैनी (इलाहाबाद) में भीड़ जुटाकर आपकी जयजयकार करा दी थी और इस बार लखनऊ में अपनी करामात दिखाने वाले हैं। आप अभी वीरू उस्ताद को छोड़िये। बाद में देखा जायेगा। फिलहाल मैं आपको एक पत्ता देता हूं। तुरुप बड़ा तो नहीं, लेकिन आजमा लीजिए। बूटा सिह ने श्यामलाल यादव का पत्ता धीरे से खिसका दिया। इसे आप कृषि मंत्रालय में फिट कर दीजिए। कम-से-कम यादव किसान तो शांत होंगे ही फिर आपको बूढ़े विद्रोही कमलापति का भी तो इंतजाम करना है। दिल्ली दरबार को बात जम गयी।

दिल्ली दरबार ने बूटा सिंह से ताश की गड्डी को जेब में छिपाने का इशारा किया और मिशन पूरा करने के लिए कहा। लेकिन बूटा सिंह ने कहा, "हुजूर आपने कइयों को 'एडीशनल चार्ज' दिया है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया।" दिल्ली दरबार ने बूटा सिंह की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, "आपके पास भी एडीशनल चार्ज रहेगा, लेकिन उसकी घोषणा नहीं होगी। आप अब 'मिनिस्टर आफ होम ऐंड रेजिगनेशन' होंगे। बूटा सिंह कुछ समझे नहीं। दिल्ली दरबार ने समझाया कि जिनको मुझे हटाना होगा, उनके इस्तीफे आप ही मागेंगे। बूटा सिंह खुश हो गये।

दिल्ली दरबार ने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वीडियो खोल दिया। देखा 'शहंशाह' फिल्म आ रही है। उन्होंने झट वीडियो बंद किया और कहा, "बूटाजी इलाहाबाद का क्या करें?" बूटा सिह अपनी तोंद पर हाथ फेर ही रहे थे कि दिल्ली दरबार ने एक पत्ता खोल दिया। "शास्त्रीजी का वास्ता देकर वोट लेने और वीपी की आक्रामकता को कम करने के लिए हरिकृष्ण शास्त्री ठीक रहेंगे"—दिल्ली दरबार ने कहा। अब धीरे से बूटा सिह ने एक चाल और चली, "हुजूर एक सिख सवा लाख के बराबर होता है, दो-दो सिखों की जरूरत क्या है।" दिल्ली दरबार समझ गये। उन्होंने मुस्कराकर ढिल्लों का पत्ता गोल कर दिया।

एक-एक करके जब सारे कोटे भर लिये गये, तो दिल्ली दरबार ने कहा, "बूटाजी अब सारे पत्ते गिनिये। बूटा सिह ने अंगूठे को थूक में भिगोया और पंजाबी में गिनती बोलते हुए पत्तों को गिना। देखा ६० पत्ते हैं। "अरे बूटाजी, ताश के तो ५२ पत्ते ही होते हैं, ये साठ कैसे?" "हुजूर २१ वीं शताब्दी को देखते हुए हमको कुछ तो नया करना ही चाहिए।" बूटा ने लंबी डकार लेकर फरमाया।

दिल्ली दरबार ने बूटा सिह से ताश की गड्डी को जेब में छिपाने का इशारा किया और मिशन पूरा करने के लिए कहा। लेकिन बूटा सिह ने कहा, "हुजूर आपने कइयों को 'एडीशनल चार्ज' दिया है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया।" दिल्ली दरबार ने बूटा सिह की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, "आपके पास भी एडीशनल चार्ज रहेगा, लेकिन उसकी घोषणा नहीं होगी। आप अब 'मिनिस्टर आफ होम ऐंड रेजिगनेशन' होंगे। बूटा सिह कुछ समझे नहीं। दिल्ली दरबार ने समझाया कि जिनको मुझे हटाना होगा, उनके इस्तीफे आप ही मांगेंगे। बूटा सिह खुश हो गये।

उन्होंने झटपट योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वोरा और दुबे ने अपने इस्तीफे वैसे ही बूटा सिह के सामने रख दिये जैसे बूटा सिह की नाक के नीचे दिल्ली में डकैतों की पिस्तौल देखकर लोग अपना माल-असबाब रख देते हैं। फिर उन्होंने टेलीफोन छाती पर लिये सोये अर्जुन सिह को और सत्ता-विरह में करवटें बदलते भागवत झा आजाद को बिस्तरों से खींचा और जहाज पर लाद कर रवाना कर दिया। साथ में चार-चार आबजर्वर कमांडो दस्तों की तरह साथ लगा दिये, ताकि गलत काम सही ढंग से संपन्न हो सके और प्रजातंत्र को वे कंधा दे सकें।

—दरबारी लाल

जनमोर्चा में अन्तर्कलह ?

अभी पिछले दिनों तक पूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहे थे, लेकिन अब वह अपने जनमोर्चा के आन्तरिक कलह में फंसते जा रहे हैं। जनमोर्चा में अब खुले तौर पर तीन राजनीतिक 'सोच' उभर आये हैं और लगता है कि आने वाले समय में इन तीनों 'सोचों' के बीच होने वाले टकराव को रोका नहीं जा सकेगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह शुरू से ही यह चाहते थे कि उनका जनमोर्चा केवल वामपंथी मोर्चे से अपना सीधा राजनीतिक संबंध स्थापित करे तथा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों के साथ एक काम चलाऊ 'एडजस्टमेंट' रखे। इससे यह होगा कि जनमोर्चा को हिन्दीभाषी राज्यों में अपना निजी प्रभाव बनाने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि वामपंथी दलों के पास इस क्षेत्र में कोई व्यापक आधार नहीं है। लेकिन रामधन, जो जनमोर्चा के संयोजक भी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस विचार से कभी भी अपने को सहमत नहीं कर पाये। उनका सोचना है कि वामपंथी दलों का हिन्दीभाषी राज्यों में अपना कोई आधार नहीं है, इसलिए ये दल जनमोर्चा को मात्र अपनी बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर जनमोर्चा जनता पार्टी, लोकदल-अ और ब के साथ अपने संबंध नहीं जोड़ पायेगा, तो वह हिन्दीभाषी राज्यों में विपक्षी दलों के त्रिकोण का एक कोण होकर रह जायेगा। अरुण नेहरू की एक अलग ही 'थ्योरी' है। उनका सोचना है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पायेगा। ऐसी स्थिति में अगर जनमोर्चा ४० से ६० सांसद जिताकर भी ले आता है, तो वह सरकार के गठन में सन्तुलन बैठाने की स्थिति में हो जायेगा।

जनमोर्चा की पिछले दिनों कई बैठकें हुई, लेकिन कौन सी 'थ्योरी' अपनायी जाये—इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया।

अभी कुछ दिनों पहले एक मजबूत राजनीतिक आधार की तलाश में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह एलान कर दिया था कि बहुत जल्दी ही जनमोर्चा अन्य तीन राजनीतिक दलों के साथ विलय करके एक नया दल बना लेगा। लेकिन उसके दूसरे दिन ही रामधन ने एक बयान जारी करके इसका खंडन कर दिया कि जनमोर्चा का विलय किसी राजनीतिक दल में नहीं होगा। रामधन ने विलय के विरुद्ध बयान क्यों जारी किया? उनका सोचना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को वामपंथी मोर्चे ने सलाह दी है कि हिन्दीभाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अलग-थलग करने के लिए बाकी सभी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर एक दल बना लें और उसके बाद संयुक्त दल वामपंथी मोर्चे से चुनावी तालमेल करे।

कुल मिलाकर इस समय जनमोर्चा में टकराव की स्थिति नहीं उभरी है, लेकिन उनके नेताओं की राजनीतिक सोच एक नहीं हो पा रही है। आरिफ मोहम्मद खान अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई काम चलाऊ समझौते पर बराबर जोर डाले जा रहे हैं। आने वाले समय में जनमोर्चा के नेताओं के आपसी टकराव को रोक पाना काफी मुश्किल-सा दिखायी पड़ रहा है।

पंडितजी का कोप

'इनसेट बी' से प्राप्त मौसम की जानकारी की तरह बनारस के कांग्रेसी हलके की नब्ज की जानकारी देश के बाकी कांग्रेसी हलके में रखी जाती है। बनारस में कांग्रेसी खेमा पैदा करने का श्रेय मरहूम श्रीमती गांधी को दिया जाता है। पं० कमलापति त्रिपाठी के प्रभाव को कम करने के लिए इंदिराजी ने सुधाकर पाण्डेय को राजनीति में चढ़ाया। जब वह इंदिराजी की सफलता-लकीर को नहीं छू सके, तो इंदिराजी ने बंदरबांट लड़ाई में श्यामलाल यादव को कांग्रेसी राजनीति में घुसेड़ दिया। और फिर तीनों खेमे एक दूसरे को टंगड़ी मारने में ही शक्ति-प्रदर्शन करते रहे जिसका नतीजा रहा कि बनारसी कांग्रेस की पहचान टूटने लगी। जहां पहले पक्ष और विपक्ष यानी पं० कमलापति त्रिपाठी समर्थक और विरोधी खेमा था, अब वहीं त्रिपाठी, पाण्डेय, यादव खेमे में शहर के कांग्रेसी बंट गये हैं और इन खेमों के लोग गाहे-बगाहे मारपीट करके अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। हाल ही में बनारस में त्रिपाठीजी के नाम के एक स्कूल में युवा कांग्रेस का दो दिन का शिविर लगा था जिसमें दो गुटों के लोग दिल्ली से पधारे पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ही मंच पर जूतम-पैजार पर उतारू हो गये।

इस करामात के कारण आयोजन तो स्थगित हो गया, पर इसकी रपट दिल्ली दरबार में पहुंचा दी गयी। [illegible] कांग्रेसियों में चर्चा है कि रिपोर्ट पहुंचने के बाद ही दिल्ली दरबार ने त्रिपाठीजी को मात देने के लिए श्यामलाल यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने का मन बना लिया। श्यामलाल यादव द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की शपथ लेते ही जहां शहर के एक कोने में नगाड़े बज उठे, वहीं पंडितजी के औरंगाबाद स्थित आवास पर मातम छा गया, क्योंकि त्रिपाठी खेमे को विश्वास था कि राजीव गांधी जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनारस को प्रतिनिधित्व देंगे, तो चंद्रा त्रिपाठी को मौका अवश्य मिलेगा।

आठ वर्ष बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनारस का प्रतिनिधित्व करने वाले श्यामलाल यादव जब १८ फरवरी को काशी में मंत्री की हैसियत से पधारे, तो उनके स्वागत की तैयारी देख करके पंडितजी के तो पांव ही फूल गये।

चर्चा यह भी है कि पिछड़े लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए ही राजीव गांधी ने श्यामलाल यादव को मंत्रिमंडल में लिया है, पर इससे सुधाकर पाण्डेय-गुट के आजकल महाबली बने राज्यसभा के सदस्य रत्नाकर पाण्डेय और त्रिपाठी खेमे में मायूसी बढ़ गयी है। पर त्रिपाठी खेमे में पंडितजी के पैंतरे की सुगबुगाहट से लोगों में आशा बलवती हो रही है कि पंडितजी अपने इस अपमान का बदला अपने पूरे राजनीतिक अनुभव को लगाकर लेंगे।

टिकैत

एक साल के भीतर महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान-नेता के रूप में जो भीमकाय रूप धारण किया है, उसके सामने दिग्गज किसान नेता बौने दिखायी देने लगे हैं। मेरठ में लगभग एक माह तक लाखों किसानों को उन्होंने अपने प्रभाव-पाश में बांधे रख कर अपनी जिस शक्ति का प्रदर्शन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह एक निर्णायक शक्ति बन गये हैं। आलोचक उन्हें धनी किसानों (कुलक) और खासकर जाटों के नेता मान रहे हैं। इन धारणाओं को निराधार तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इतना तय है कि किसानों को एक झंडे तले लाने की उनमें क्षमता है। बड़े-बड़े प्रदर्शन और घेराव आयोजित करने का टिकैत को कोई अनुभव नहीं। ऐसी स्थिति में भारी भीड़ जुटाना, उसे अनुशासित रखना उनके खाने-पीने की व्यवस्था करना बड़ी बात है। शुरू के पंद्रह-बीस दिनों में किसानों ने जिस शांति का परिचय दिया, वह अभूतपूर्व है। यदि छात्र इस आंदोलन में न कूदते, तो बाद में भी किसानों का यह आंदोलन हिंसक मोड़ न लेता। कुल मिलाकर डेढ़ दर्जन किसानों ने इस आंदोलन में प्राण गंवाये हैं।

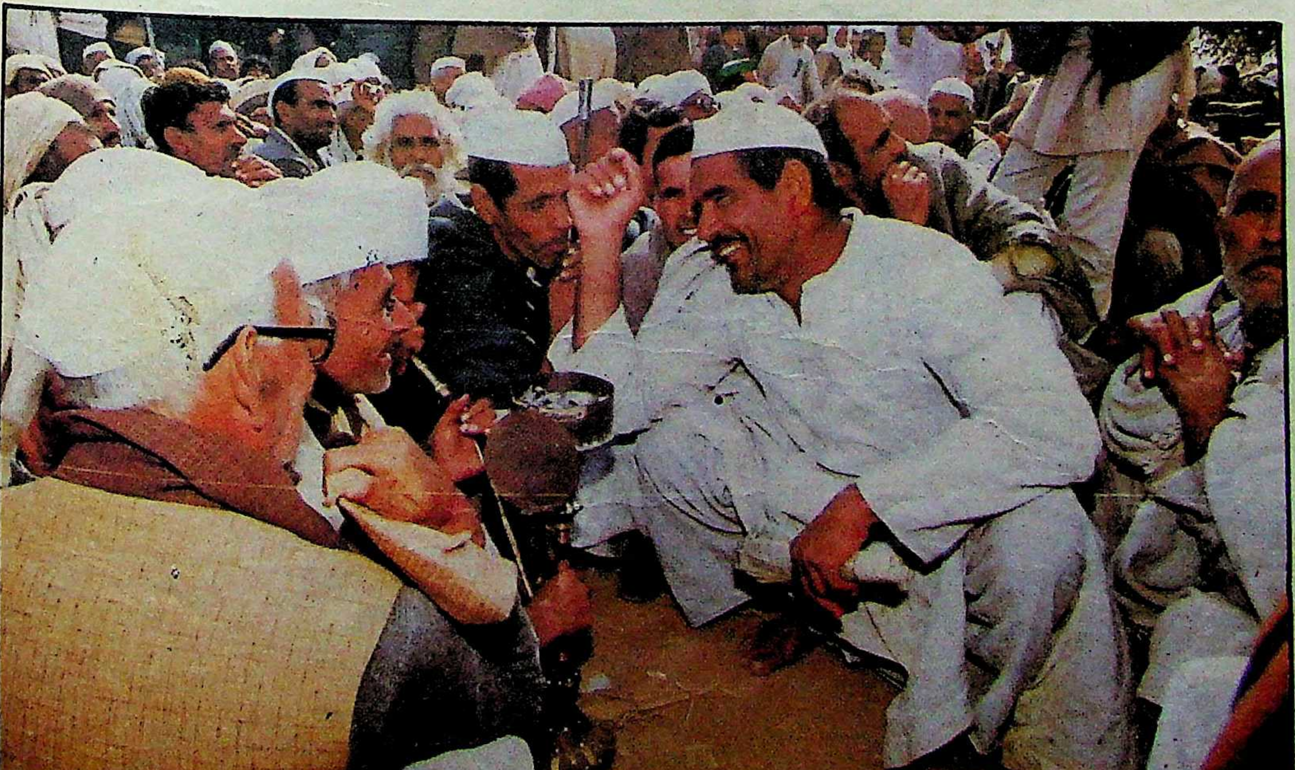

छाया : मनमोहन शर्मा

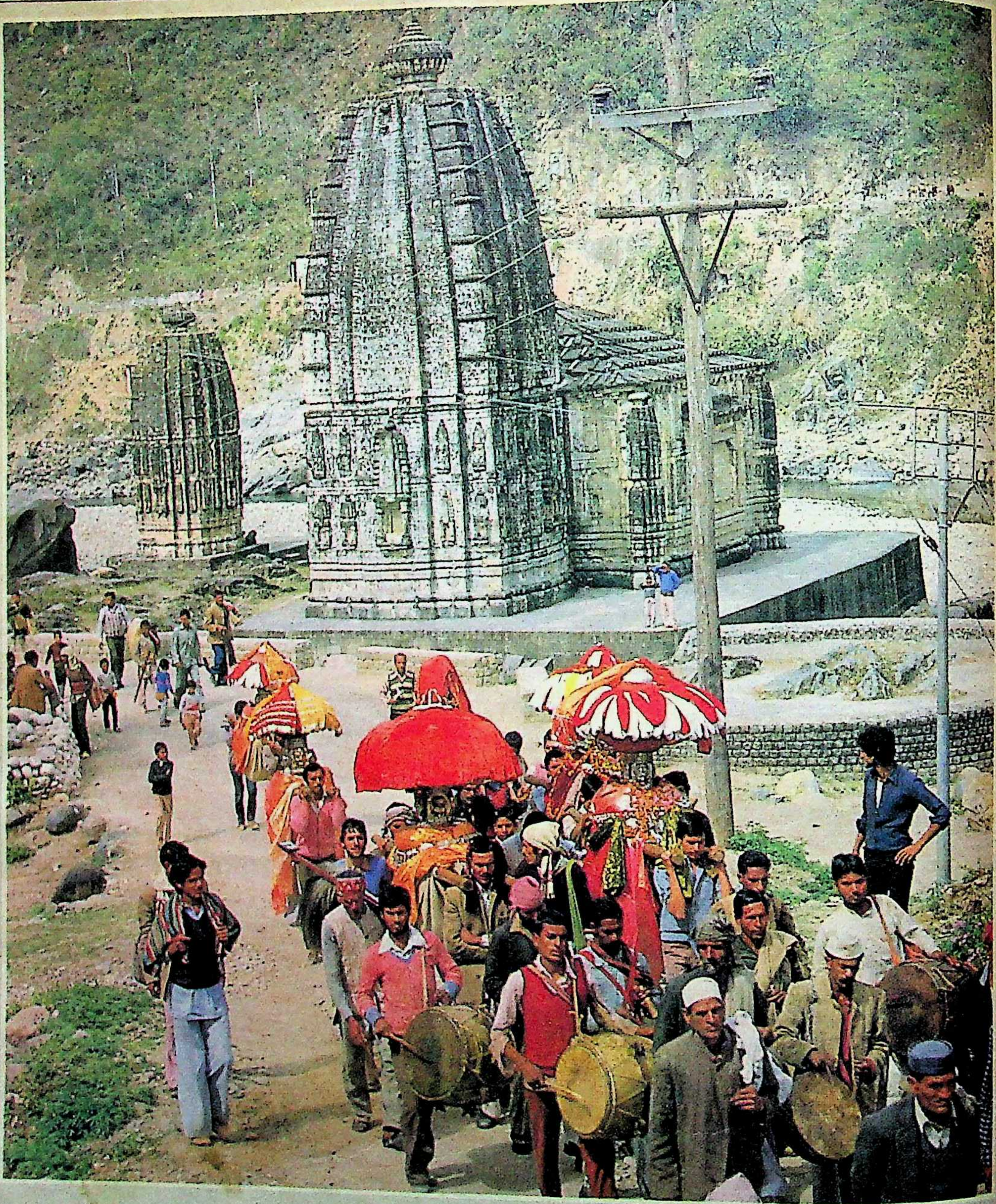

मंडी में महाशिवरात्रि

यों तो पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास और भक्ति-भाव के साथ मनाया जाता है, लेकिन मंडी (हिमाचल प्रदेश) के शिवरात्रि मेले की छटा कुछ अलग है। सैकड़ों वर्षों से मंडी में यह मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले में शिव की विभिन्न मुद्राओं और अन्य देवी-देवताओं की झांकियां निकाली जाती हैं और शिव मंदिर में पारंपरिक ढंग से पूजा-अर्चना की जाती है। यहां दिये गये चित्रों में मंडी के शिवरात्रि महोत्सव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है।

छाया : दिलीप सिन्हा

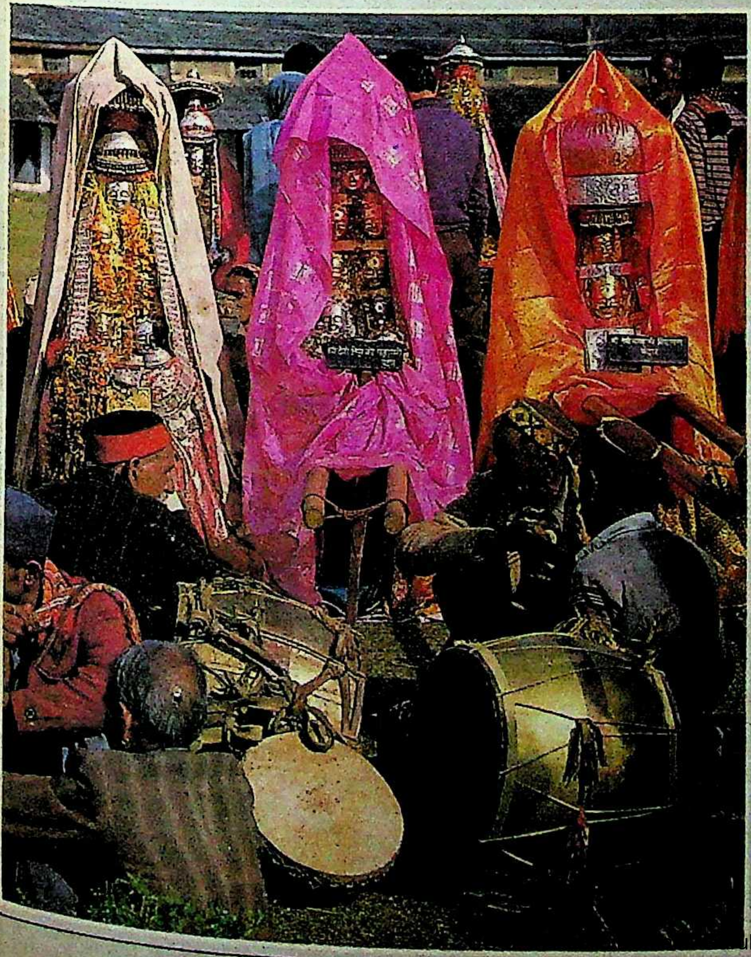

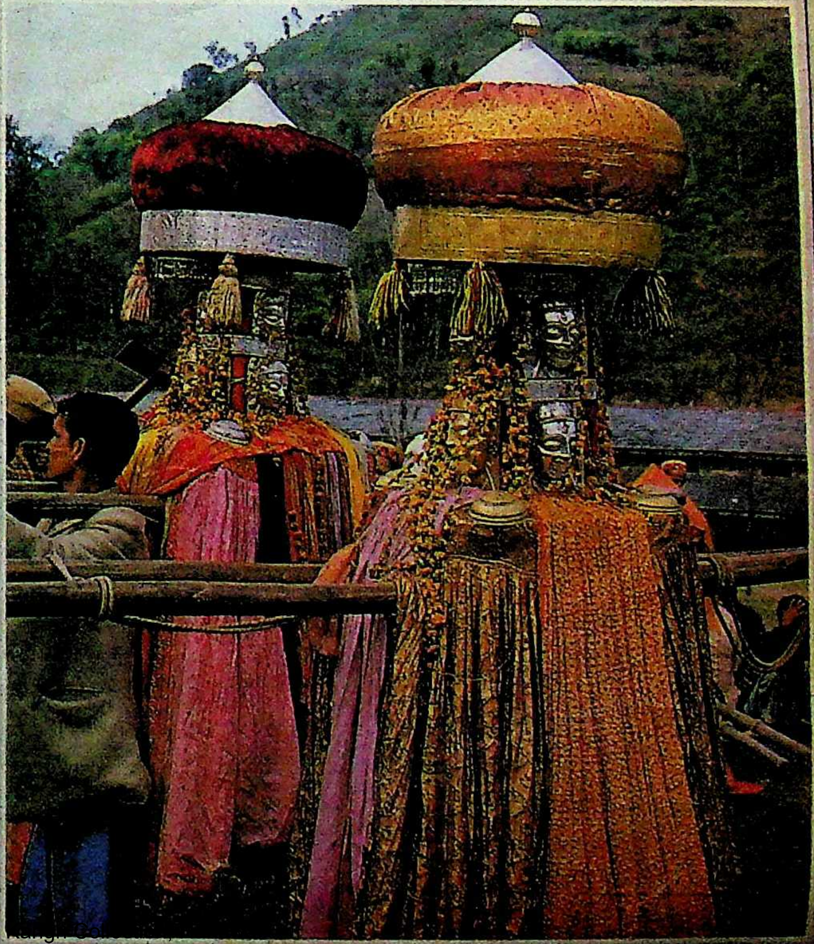

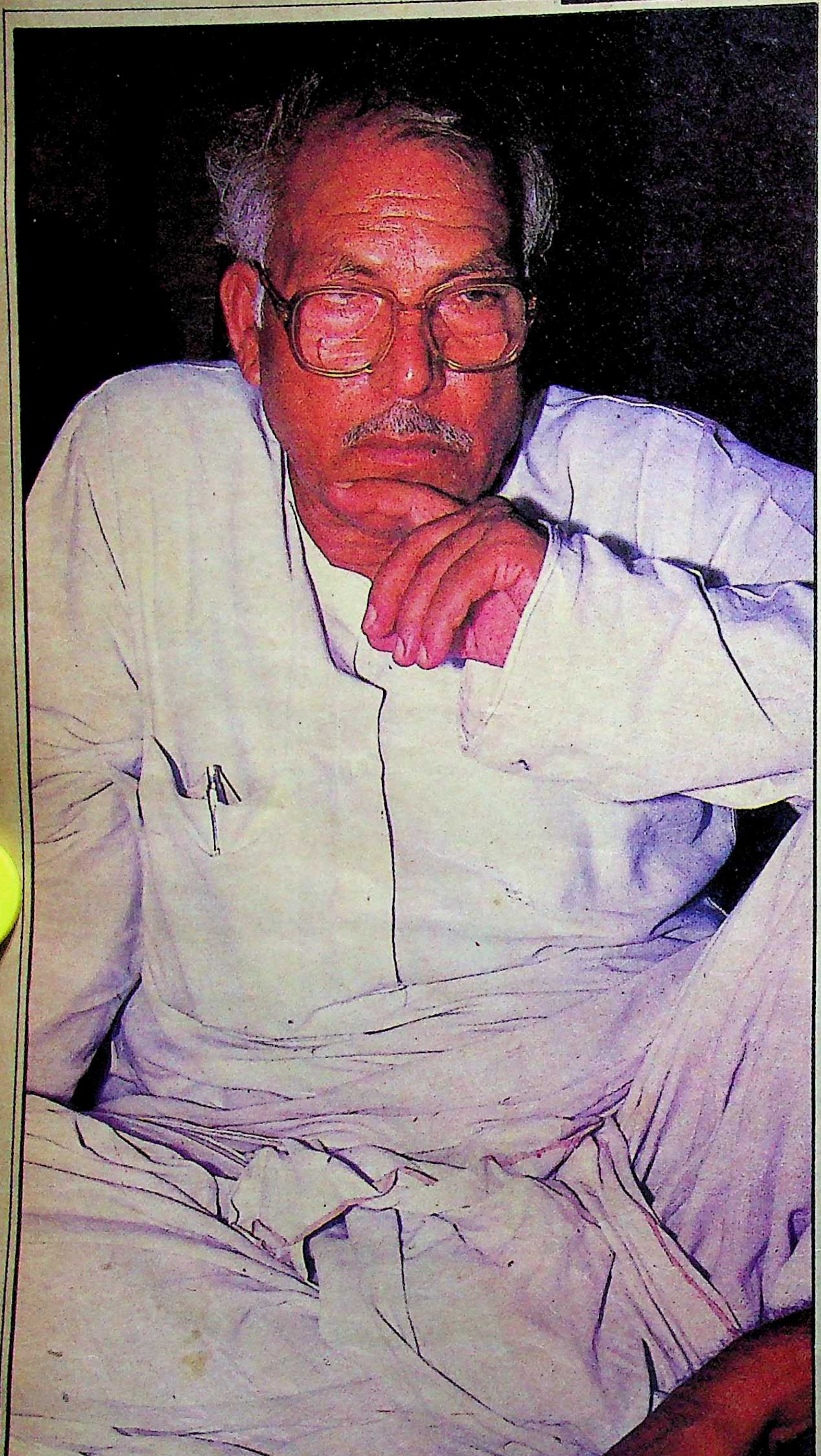

कर्पूरी ठाकुर

हक मांगते गरीबों की तनी हुई मुट्ठियों की सामूहिक शक्ति के प्रतीक—कर्पूरीजी—अब नहीं रहे। जिस दिल में वह वंचितों का दर्द समोये हुए थे, उसे १७ फरवरी, १९८८ को मौत ने अचानक अपने क्रूर पंजे में जकड़ लिया। अपनी जिंदगी के ६७ वर्षों में से ५० वर्ष कर्पूरीजी ने लड़ते हुए गुजारे—पहले अंग्रेजों से और फिर उन लोगों से जो आजादी के सुख को अंतिम पांत में खड़े लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। इस लड़ाई के कारण उन्हें लगभग २० बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों की जेल से तो उनकी मुक्ति उस दिन हुई थी, जिस दिन देश मुक्त हुआ था।

कर्पूरीजी उन गिने-चुने लोगों में से थे, जिनका कार्य-क्षेत्र मुख्यतया एक प्रांत था, लेकिन जिनकी लोकप्रियता देशव्यापी थी। कर्पूरीजी दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर १९७० से जून १९७१ तक उन्होंने संविद सरकार का और १९७७ से १९७९ तक उन्होंने जनता सरकार का नेतृत्व किया। १९५२ से निरंतर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे कर्पूरीजी १९७७ में समस्तीपुर से लोकसभा के लिए भी चुने गये थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कारण उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ दी थी। इस समय वह लोकदल-ब के एक शक्तिशाली स्तंभ थे और विपक्षी एकता के लिए जुटे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि उनका सपना साकार होता, वह संसार में नहीं रहे। लेकिन उनका संघर्ष, उनके जीवनादर्श आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

छाया : दीपक कुमार

बिना विवाह के पति-पत्नी

'गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है शादी-ब्याह, आटे दाल का भाव मालूम हो जायेगा बेटा जिस दिन कंधे पर जुआ रखा जायेगा, ऐसा कहते हैं,' बड़े-बुजुर्ग। इसके अलावा भी बैंड-बाजे, अगुवा, नाई, बाराती तथा तरह-तरह के तामझाम। कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक अदद बीवी नसीब होती है और शादी के बाद के उसके नक्शों का तो कोई पुछत्तर ही नहीं। शायद इसीलिए संसार के कई मुल्कों में इन सबका झंझट ही नहीं पालते, फिर बिल्ली के गले में कौन बांधे घंटी? वैसे भी विदेशों में उन्मुक्त विचरण को बुरा नहीं माना जाता। न तो वहां पुरुष-वेश्याओं की कमी है, न गे क्लबों की ही। यों तो स्वीडन सरकार आपसी शारीरिक संबंधों और स्वतंत्र जीवन-रीति की पक्षधर रही है। वहां कितने ही जोड़े बिना विवाह के जीवन का आनंद लूटते हैं, लेकिन इधर स्वींडन ने प्रेमी-जोड़ों को बिना विवाह के एक साथ पति-पत्नी के रूप में रहने की इजाजत देकर कमाल ही कर दिया है। यही नहीं, ऐसे जोड़ों को संपत्ति पर भी समान अधिकार होगा चाहे भले ही दोनों में से संपत्ति एक ही की रही हो। कोढ़ में खाज यह कि इसमें बालप्रेमी भी शामिल हैं। बस उन्हें शिकायत है, तो इतनी कि उन्हें विवाह करके बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे देश में भी बालप्रेमियों की कमी नहीं है, लेकिन अभी वे इतने बेहया नहीं हैं कि शादी-विवाह जैसी बातें करें। वैसे चुपकें-चुपके तो हर तरह की कारगुजारियां करने में वे भी आगे ही हैं।

तैरनेवाली रेलगाड़ी

हिंदुस्तान पुराने जमाने से ही करिश्मों का देश रहा है। यहां एक-से-एक ऋषि हुए हैं जो अपनी गुप्त विद्या से पानी पर खड़ाऊं पहनकर चल सकते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सशरीर जा सकते थे, हवा में उड़ सकते थे लेकिन अब न वे ऋषि-मुनि रहे और न उन विद्याओं को जाननेवाले। अब तो उन करिश्मों का स्थान ले लिया है साइंस ने। तकनीक के मामले में जापान का कोई जवाब नहीं।

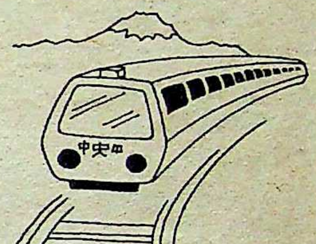

उसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है, हवा में तैरती तीव्रतम गतिवाली रेलगाड़ी की ईजाद कर। इसकी खोज में वहां के वैज्ञानिक १९६२ से ही लगे हुए थे। दुनिया भर में सुपर कंडिक्टिविटी (अति संवाहकता) के जरिये चुंबक से चलने वाली यह पहली रेलगाड़ी है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यह रेलगाड़ी चुंबक के कारण पटरियों पर न चलकर हवा में तैरती हुई चलेगी। मियाजाकी के रेल तकनीकी अनुसंधान के हवाले से बताया गया है कि यह रेलगाड़ी ५१७ किमी० प्रति घंटा की चाल से चलेगी। ध्यान रहे कि कंप्यूटर नियंत्रित यह गाड़ी बिना चालक के होगी तथा अत्यंत तेजी से चलने के कारण यात्रियों को अपने को पेटियों से बांधना पड़ेगा। चूंकि रेल पटरियों पर ३०० किमी० प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक तेज गाड़ियां नहीं चलायी जा सकतीं, और जापानी वैज्ञानिक अपने यहां चलनेवाली बुलेट रेलगाड़ियों की रफ्तार से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए इस नयी गाड़ी की ईजाद की है। इसमें बैठनेवाले यात्रियों को एक ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि चुंबक के कारण उनकी घड़ियां जाम हो जाती हैं, लेकिन जापानी वैज्ञानिकों के लिए इससे छुटकारा पाना कोई कठिन बात न होगी।

अब खाइये भुना हुआ घड़ियाल

खाने के मामले में तो आदमी का कोई जवाब ही नहीं। उसके लिए चींटी, टिड्डी, छिपकली, मेढक, सांप, बिच्छू तो भक्ष्य रहे ही, जरूरत पड़ने पर उसने आदमी तक को खाया है, लेकिन वह घड़ियाल खा सकेगा, विश्वास नहीं होता। अभी तक तो घड़ियाली आंसू ही मशहूर थे, लेकिन अब भुना हुआ घड़ियाल भी मिल सकेगा। होंडुरास सरकार की घड़ियालों पर विशेष कृपा हो गयी है। वह पूरा-का-पूरा उद्योग ही स्थापित करने जा रही है। उसने बतौर प्रयोग एक घड़ियाल-फार्म त्रुजिलो के उत्तरी बंदरगाह पर तथा अनेक व्यावसायिक फार्म कैरेबियन तट के दलदली किनारों पर शुरू कर दिया है। यों तो होंडुरास सरकार पहले से ही केला और कहवा की प्रमुख निर्यातक देश रही है, लेकिन अब वह पशु-पक्षियों—विशेषकर छिपकली से तोते तक के फार्म विकसित कर रही है। घड़ियाल से उसे दो फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो विदेशों को वह भुना घड़ियाल निर्यात करेगी, दूसरे उसके चमड़ों को वहां भेजेगी जहां उसके बैग और पेटियां बन सकेंगी। देखना है कि भारत इनमें से क्या आयात करता है?

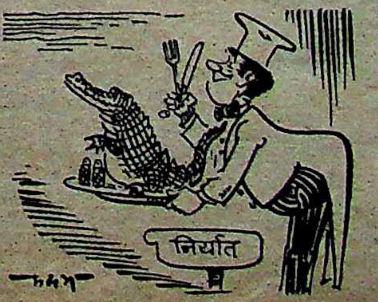

दूसरा जन्म

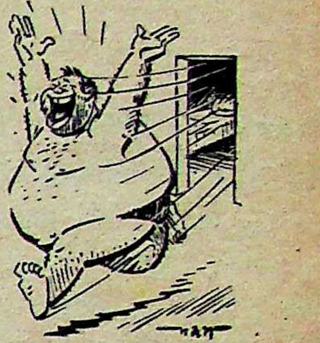

कहते हैं, एक तंदुरुस्ती लाख नियामत। हमारे ही देश में नहीं यह जुमला सर्वत्र प्रचलित है। अंग्रेजी में तो कहते ही हैं 'हेल्थ इज वेल्थ'। जो आवश्यकता से अधिक दुबले-पतले होते हैं, वे संतुलित भोजन और दवा-दारू पर जोर देते हैं, लेकिन जो पीपे जैसे मोटे हैं, वे डाइटिंग तथा तरह-तरह की कसरत करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। स्त्रियां तो खासकर इस ओर विशेष ध्यान देती हैं ताकि वे बेडौल न हो जायें। इसी प्रकार अपने मोटापे को लेकर चिंतित रहनेवाले सज्जन हैं, ४२ वर्षीय वाल्टर हडसन। हडसन अपने बेशुमार वजन (५६६ किलोग्राम) की वजह से १६ वर्षों तक कमरे में ही पड़े रहे। जब उनका वजन घटकर १६९ किलोग्राम हुआ तब वह कहीं ज़ाकर कमरे से बाहर निकल रोशनी देख पाये। कमरे से बाहर निकलने पर उन्होंने महसूस किया कि उनका दूसरा जन्म हुआ है। अपने बाहर निकलने को वह क्रिसमस का उपहार मानते हैं। बेचारे हडसन अपने मोटापे से इतने तंग थे कि कोई कपड़ा ही नहीं पहन पाते थे, नंगे ही रहते थे। पहली बार उनको तब कपड़ा पहनना पड़ा जब वह प्रेस कांफ्रेंस में आये। दर्जी ने बताया कि उनकी कमीज सात गज में बन सकी। मृदुभाषी हडसन का कहना था, "एक दिन मैं बाहर निकलूंगा अवश्य, लेकिन मैं यह नहीं पसंद करता कि मुझे कोई धक्का देकर बाहर निकाले।" इस समय भी हडसन का नाम मोटापे के कारण 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स' में दर्ज है।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है, इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी-कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है।

राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या

– भीष्म साहनी

मैं भाषाविद् नहीं हूं। भाषाएं कैसे बनती हैं और विकास क्रम में कैसे बदलती हैं, इस बारे में बहुत कम जानता हूं, इसलिए किसी अधिकार के साथ इसके सवाल पर कुछ नहीं कह सकता। मेरी अपनी स्थिति भी अनूठी ही है। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई है, लिखता मैं हिंदी में हूं और पढ़ाता था मैं अंग्रेजी। आप कहेंगे, ऐसा व्यक्ति न घर का, न घाट का। जो चार जबानों से वास्ता रखता हो, वह किसी एक जबान का भी नहीं हो सकेगा।

पर शायद ऐसी स्थिति से मुझे कुछ लाभ भी है। भाषा के सवाल पर मात्र भावना के स्तर पर लिये गये निर्णय और उससे पैदा होने वाली अतिरंजना और सिर-फुटौव्वल से बचा रहता हूं। अंग्रेजी को छोड़ता तो खाता कहां से, हिंदी को छोड़ दूं, तो जिंदगी भर का किया कराया कुएं में, पंजाबी को कैसे छोड़ सकता हूं, वह तो मेरे खून में है और उर्दू को कैसे छोड़ूं, वह तो मुझे संस्कार रूप में मिली है। मुझे ये सभी भाषाएं प्यारी हैं।

किसी एक को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इनकी उपयोमिता से इनकी देन और महत्व से परिचित हूं और शायद इसी कारण मैं इस सवाल पर लिखने-बोलने का दुःसाहस भी कर बैठा हूं।

कौन नहीं जानता कि भाषा के सवाल को लेकर हमारे देश में तरह-तरह की विडंबनाएं पायी जाती हैं। आजादी के बाद स्थिति बहुत कुछ बदली। जिस उदार दृष्टि की जरूरत थी, वह नहीं रही। हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषी देश है। सभी लोग अपनी-अपनी जबान से प्यार करते हैं और सभी अपनी-अपनी जबान से जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर, सबसे मीठी भाषा होती है। उसमें उसकी मां की आवाज बोलती है, सैकड़ों-हजारों वर्षों की संस्कृति बोलती है, उसमें वह अपने दिल की धड़कनें सुनता है। इसलिए जबान का मसला नाजुक मसला है। इसे दूसरे का दिल दुखाकर, अपनी भाषा को ऊंचा और दूसरे की भाषा को छोटा कहकर नहीं सुलझाया जा सकता।

पिछले कुछ सालों में जहां हिंदी का पठन-पाठन बढ़ा है, वहीं अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी की लोकप्रियता कम हुई है। एक जमाना था, जब दक्षिणी भारत में बड़े उत्साह से हिंदी का अध्ययन किया जाता था। मेरे एक तमिल मित्र दस वर्षों तक बहुत ही मामूली वेतन लेकर एक स्वयंसेवक की तरह हिंदी अध्यापन का काम तमिलनाडु में करते रहे थे। पर अब स्थिति बदल गयी है।

भाषा के सवाल को लेकर सबसे बड़ी भूल जो हमारे देश में हुई है, वह इसे धर्म के साथ जोड़ना था। यह भूल अभी भी की जा रही है और यदि आगे भी ऐसे ही चलता रहा, तो इसके बड़े दुःखद परिणाम निकलेंगे।

इस दृष्टि से सबसे विकट स्थिति उर्दू भाषा की रही है। उर्दू की कहानी भी अनूठी कहानी है। देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित की। हमारे यहां लोगों ने कहा, ठीक ही तो है, पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं, मुसलमानों की जबान उर्दू ही तो है। पर कुछ ही साल बाद पूर्वी पाकिस्तान—जो अब बांगला देश कहलाता है—के मुसलमानों ने कहा कि हमारी भाषा तो बंगाली है, उर्दू नहीं है। इसके कुछ ही दिन बाद पश्चिमी पंजाब के मुसलमान कहने लगे कि हमारी मातृभाषा तो पंजाबी है और सिंध के मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी भाषा सिंधी है और सीमा प्रांत के मुसलमानों ने कहा कि उनकी जबान पश्तो है। ये आवाजें उठीं जरूर, लेकिन सांप्रदायिकता का जोर वहां पर भी ज्यादा होने के कारण ये आवाजें दब गयीं। पर सवाल जरूर उठता है, अगर उर्दू जबान मुसलमानों की है, तो बांगलादेश के मुसलमान उर्दू को क्यों नहीं अपना पाये?

हमारे यहां ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनके अंदर ऐसे भाग पाये जाते हैं, जहां भारी संख्या में बसे हुए लोगों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा न होकर दूसरी भाषा है, जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का इलाका, जहां उर्दू बोली जाती है, बंबई में बसे हुए हिंदी-भाषी, पंजाबी-भाषी तथा अनेक अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग। लेकिन इससे भी हम यह नतीजा नहीं निकालते कि उनकी भाषा धर्म से जुड़ी है।

हर प्रदेश की अपनी भाषा है। लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू रहते हुए भी आप यह कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो यह आपकी अपनी सांप्रदायिकता ही है और कुछ नहीं।

सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है, इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी-कभी कहा जाता है कि यह भाषा है और कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है।

कभी यह भी कहा जाता है कि उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं है, वह मात्र अलग लिपि है। यदि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है और उनकी दो लिपियां हैं, तो आप दोनों लिपियों को मान्यता दे दीजिए। इसमें क्या

दिक्कत है? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस साझी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है और वह देवनागरी लिपि है। इसके पीछे तो यही जेहनियत काम कर रही है कि लिपि को मारो, जबान अपने आप मर जायेगी। एक हवा उठी थी कि उर्दू को देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए। चूंकि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है, इसलिए उर्दू के कवि भी वास्तव में हिंदी के ही कवि हैं। पर जब पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं, तो गालिब, मीर और उर्दू के अन्य कवियों का कहीं नाम नहीं। कहीं एकाध कवि को लेकर आलुओं पर से मिट्टी पोंछी गयी थी। अगर इसके पीछे सच्चा विश्वास होता, तो कौन नहीं जानता कि गालिब न केवल भारत के, बल्कि संसार भर के महान कवियों में माने जाते हैं और उर्दू साहित्य ने हमारे देश के साहित्य को चार चाद लगाया है। यदि सचमुच हमें इस साहित्य से प्रेम होता, तो उसे सुरक्षित और अधिक विकसित कर पाने के लिए, उसे पूरी-पूरी मान्यता देते और उस भाषा और साहित्य की परंपराओं को जीवित रख पाने के लिए भरसक प्रयत्न करते। हमारी स्थिति की विडंबना यह है कि हम कभी तो उर्दू के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और कभी केवल कागजी तौर पर उसके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। जब कागजी मान्यता देते हैं, तो उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू बोर्ड खड़ा करते हैं, लाखों करोड़ों की रकम जुटाते हैं, लेकिन व्यवहार में उसके अस्तित्व को मान्यता नहीं देते। यह नीति ठीक ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ की शाख-पत्तियों पर तो पानी छिड़को, लेकिन पेड़ की जड़ काट दो। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि उर्दू फले-फूले, तो आप ही का यह फर्ज हो जाता है कि आप स्वयं इस बात का अध्ययन करें और उसे उसके प्रदेश में बहाल करें, उसे सरकारी मान्यता मिले, स्कूलों-कालेजों में बाकायदा उर्दू पढ़ाई जाने लगे, उर्दू की शिक्षा जड़ पकड़े, बढ़े। कभी अनुदानों से भी भाषाएं जीवित रह पायी हैं?

यदि उर्दू के साथ न्याय नहीं किया गया, तो हम सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पायेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है। यह भाषा के सवाल को जानबूझ कर सांप्रदायिकता का रंग देना है। कौन नहीं जानता कि उर्दू का जन्म हमारे अपने देश में हुआ था। हमारे ही देशवासियों की प्रतिभा ने उसे विकसित किया है, निखारा है। ७०० बरस पहले जहां से आक्रमणकारी आये थे, वहां की जबान न तब उर्दू थी, न आज है। और यदि आक्रमणकारियों की जबान को आप मान्यता नहीं देना चाहते, तो संस्कृत भी तो आक्रमणकारियों की ही जबान थी। यह सवाल को जानबूझ कर सियासी रंग देना है। किसी भाषा पर विचार करते समय न तो हम इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उस भाषा के बोलनेवालों का धर्म क्या है और न इस बात को कि वे आक्रमणकारी हैं, अथवा नहीं। कौन नहीं जानता कि ये आक्रमणकारी मूलतः हमारी अपनी जाति के ही लोग थे।

यह एतराज भी उठाया जाता है कि उर्दू में भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है, साकी और पैमाना की, गुल-ओ-बुलबुल की, आदि-आदि। क्या यह सच नहीं कि रेनेसा (पुनर्जागरण) काल में सारे यूरोप के साहित्य पर यूनानी और रोमन पुराण कथाओं की भरपूर छाप पड़ी थी, जो अब इन देशों के साहित्य का अभिन्न अंग बन गयी है। क्या उससे अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी साहित्य नहीं रह गया था, या अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा नहीं रह गयी थी?

इसमें शक नहीं कि भावनात्मक लगाव के कारण हम अपने सहधर्मियों से जुड़ते हैं, अपनी जाति के लोगों से जुड़ते हैं, पर भाषा उनमें एक तत्व होती है और वह भी कई बार निर्णायक तत्व नहीं होती। कहीं पर एक जाति के लोगों के धर्म अलग-अलग होते हैं, पर भाषा एक होती है, कहीं-कहीं पर धर्म एक होता है, पर भाषाएं अलग-अलग होती हैं। रूस में रहने वाले यहूदियों की भाषा रूसी है, जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की भाषा जर्मन है, इंग्लैंड में रहने वाले यहूदियों की भाषा अंग्रेजी है, भले ही धर्म सभी का एक है और भावनात्मक स्तर पर वे यहूदी धर्म और यहूदी भाषा से जुड़े हैं।

हमारी स्थिति की विडंबना भाषा में शुद्धता पर जोर देने में भी पायी जाती है। शुद्ध भाषा का मसला भी सांप्रदायिकता की ही देन है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मतलब कि संस्कृतनिष्ठ होनी चाहिए। हिंदी भाषा में शुद्धता की मांग भी बहुत हद तक उर्दू को ही लक्ष्य करके की जाती है। उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाये, तो कुछ लोगों को चिढ़ होती है, अंग्रेजी का शब्द आ जाये, तो इतनी चिढ़ नहीं होती, बल्कि कहीं-कहीं पर तो खुशी होती है, क्योंकि इससे बौद्धिकता का, आधुनिकता का रंग आता है।

हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे सियासतदा भाषा को हांकते रहे हैं। भाषा के नाम पर लोगों को हांका नहीं जा सकता। मैं तो कहूंगा कि सियासतदानों को भाषा के पीछे-पीछे चलना चाहिए, उसके विकास-क्रम को समझना चाहिए, भाषा खुद उन्हें रास्ता दिखायेगी, भाषा के आगे-आगे चल कर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। हिंदी में से उर्दू के शब्दों को चुन-चुन कर निकालने का काम, हिंदी के अंदर, संस्कृत के शब्द ढूंढ़-ढूंढ़ कर ठूंसने का काम, हमारे सियासतदानों के ही हुक्म पर होता रहा है। 'सिगरेट पीना मना है' काट कर आपने 'धूम्रपान वर्जित है' लिख दिया, यह अपने मतानुसार भाषा को चलाने की चेष्टा है, उसे हांकने की कोशिश है, वरना आप जन-जीवन में पाये जाने वाले बोलचाल के शब्दों को क्यों नहीं अपनाते?

> **हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे सियासतदां भाषा को हांकते रहे हैं। भाषा के नाम पर लोगों को हांका नहीं जा सकता। मैं तो कहूंगा कि सियासतदानों को भाषा के पीछे-पीछे चलना चाहिए, उसके विकासक्रम को समझना चाहिए, भाषा खुद उन्हें रास्ता दिखायेगी, भाषा के आगे-आगे चल कर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए।**

भाषा का सवाल न तो स्कूलों-कालेजों की शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संतोषजनक ढंग से सुलझ पाया है, न विज्ञान और टेक्नालाजी के क्षेत्र में, न संस्कृति के क्षेत्र में और न ही प्रशासन के क्षेत्र में, क्योंकि इसे हल करने की कोशिश के पीछे भाषाई अंधराष्ट्रवाद अथवा संकीर्ण सांप्रदायिकता काम कर रही है। क्या कारण है कि अनेक देशों ने इसे सुभीते से हल कर लिया है, जबकि हमारे यहां यह और ज्यादा पेचीदा होता चला गया है। स्विट्जरलैंड में तीन भाषाओं में सरकार का सारा काम चलता है, फ्रेंच, जर्मन और स्विस भाषाओं में और स्विट्जरलैंड छोटा-सा देश है। वहां किसी एक भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता था और उसे ऊंचा दर्जा देकर अन्य भाषाओं को सहयोगी भाषाओं का दर्जा दिया जा सकता था। पर वहां भाषा के सवाल पर जात-पांत नहीं बरती जाती। हमारे यहां हर बात में जात-पांत, ऊंच-नीच चलती है। किसी भी समस्या को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने-आंकने में असमर्थ होते जा रहे हैं। जब तक विवेकपूर्ण, तर्कसंगत, सद्भावनापूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती, उस वक्त तक यह प्रश्न हमारी प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बना रहेगा। ■

एन०टी० रामाराव

राजीव राज्यों को बहुत कमजोर बना रहे हैं

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदामुरि तारक रामाराव वेंकटेश्वर के भक्त हैं और नियति पर भरोसा करते हैं। यद्यपि उन्हें आंध्र विधानसभा में प्रचण्ड बहुमत प्राप्त है, तथापि उनका मुख्यमंत्री का सिंहासन जब-तब डोलने लगता है। हाल ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तो अपने १३६ पृष्ठीय एक फैसले में रामाराव को दोषी ठहराया ही है, राज्यपाल कुमुदबेन जोशी ने भी गणतंत्र दिवस के भाषण में एन०टी०आर० सरकार की आलोचना की है। तेलुगुदेशम की मान्यता है कि वह राज्य सरकार को बदनाम करने और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस-इ को मजबूत करने के लिए जो कुछ कर सकती हैं, कर रही हैं। लेकिन रामाराव चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं। उच्च न्यायालय के फैसले के असर को खतम करने के लिए रामाराव ने ६ जनवरी, १६८८ को परेड ग्राउंड में अपने छह लाख से अधिक समर्थकों के बीच विशाल सभा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राज्यपाल जोशी के गणतंत्र दिवस पर दिये भाषण के विरोध में अपने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करके उन्होंने राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा। साथ ही अखबारों में विस्तार से यह खबर भी छपी कि फिजूलखर्च राज्यपाल जोशी ने राजभवन के खर्चों के लिए निर्धारित धनराशि से १६ लाख रुपए अधिक खर्च कर दिये हैं। हाल ही रामाराव ने ऋषि विश्वामित्र पर फिल्म निर्माण की घोषणा की है, जिसमें विश्वामित्र की मुख्य भूमिका वह स्वयं अभिनीत करेंगे। गेरुआ वेश में आंध्र की जनता की धार्मिक भावनाओं को उभार कर लोकप्रियता प्राप्त करने का फिल्म से बेहतर कोई अन्य माध्यम नहीं है। विजय दत्त ने हैदराबाद में और पद्मा शास्त्री ने दिल्ली में रामाराव से विस्तार से बातें की हैं। रामाराव अपनी भावी योजनाओं के प्रति यद्यपि चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका की संभावना से इनकार भी नहीं करते। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

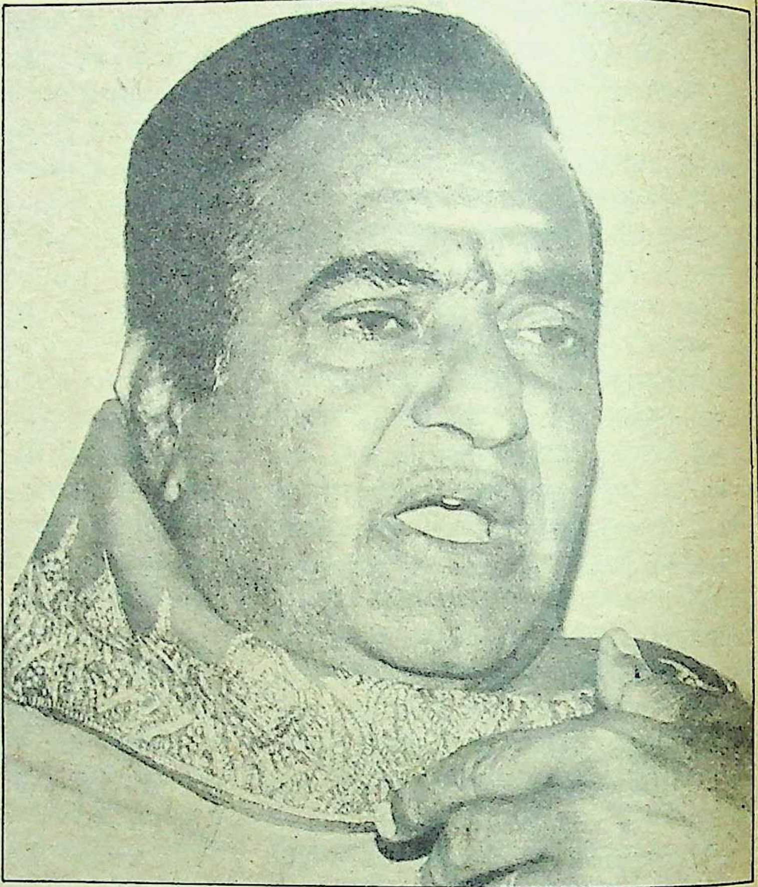

माया: **राजीव के प्रधानमंत्री रहते, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य आपको कैसा लगता है?**

रामाराव: हमने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं। जब राजीव गांधी सत्ता में आये थे, तो हमें लगा कि एक तेज-तर्रार नौजवान सत्ता में आ रहा है और वह हमारे महान नेताओं के सिद्धांतों पर चलते हुए लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायेगा। लेकिन ये लोग जनता के साथ न्याय करने में असमर्थ रहे हैं, ये लोग बुरी तरह असफल रहे हैं। मैं तो बहुत निराश हूं।

माया: इन वर्षों में राजीव गांधी का व्यवहार कैसा रहा है?

रामाराव: अगर किसी के बारे में कुछ बातें और उसके सोच का पता हो, तो मिलने का अर्थ भी होता है। असली विचार-विमर्श तो तभी होता है, जब आपके दिल में इसके लिए जगह और इच्छा हो।

माया: आप कहा करते थे कि तेलुगु लोगों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायी गयी है। क्या आपके सत्ता में आने से यह प्रतिष्ठा बढ़ी?

रामाराव: इंका ने तेलुगु लोगों के साथ बहुत नीच व्यवहार किया। हमने लोगों को एक स्थायी सरकार दी है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को मदद पहुंचाना है। हम उनका संरक्षक बनना चाहते हैं।

माया: वहां के कांग्रेसी भी तो तेलुगु हैं?

रामाराव: हुआ करें। पर हमारी नीतियां लोगों को समर्पित हैं। हमारे लिये समाज कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि दो रुपए किलो चावल देना समाज कल्याण नहीं है। मैं तो उनकी बुद्धि पर तरस ही खा सकता हूं। आप लोगों को मारकर मानव-शक्ति नहीं पैदा कर सकते। स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क और थोड़ी खुशीवाले आम लोगों के अस्तित्व के लिए सबसे पहली चीज है, भोजन। इसीलिए हमने दो रुपए किलो चावल देने की नीति लागू की। गरीब लोगों को चावल के अलावा आधे दाम पर कपड़ा और स्थायी घर देने की हमारी योजना है। कांग्रेस के राज में तो वे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते थे।

माया: गैरइंका राज्य सरकारों की शिकायत रहती है कि वित्तीय मामलों में केन्द्र का रुख सहयोग का नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इन योजनाओं को कैसे चला पा रहे हैं?

रामाराव: १६८३ में आंध्र प्रदेश का बजट ६३० करोड़ रुपए का था और अब यह १२५० करोड़ रुपए का हो गया है। यही बताता है कि हमने राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि कर ली है और इसी प्रकार हम अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। यह तो सिर्फ एक ही मामला है। हमने औरतों को बराबरी का दर्जा दिया है। राज्य में अब चार विश्वविद्यालय हैं—एक सिर्फ तेलुगु भाषा के लिए, एक खुला विश्वविद्यालय, एक महिलाओं के लिए और चौथा मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए। अब हम ग्रामीण विकास के लिए पांचवां विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें नगरों और शहरों में रहने-बसने का लालच छोड़ना होगा।

माया: शिवशंकर का आपके साथ दुर्व्यवहार करने का क्या मामला है?

रामाराव: ऐसा कुछ नहीं था। छोड़िए इन बातों को वह अपनी स्थिति जानते हैं और मेरी भी। मैं जिस पद पर हूं, इससे उनकी हर बात

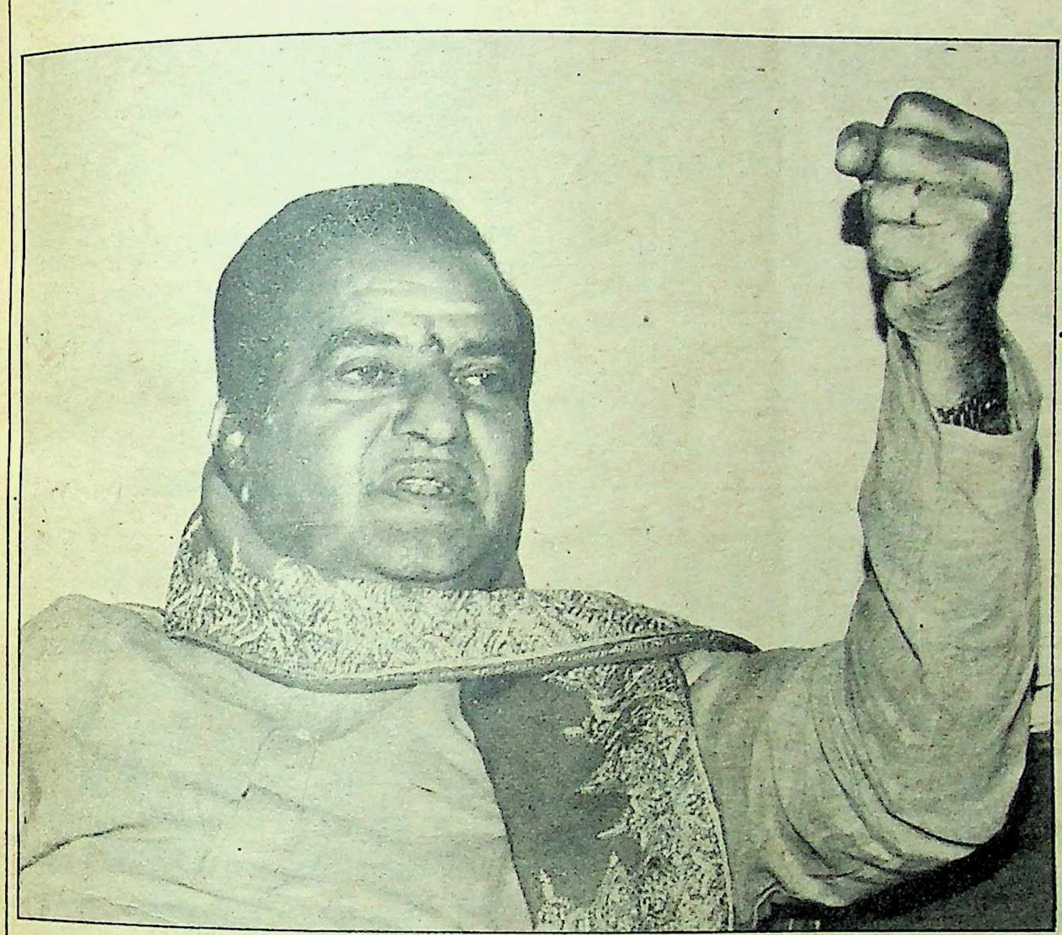

लोकतंत्र को हर आदमी का खयाल रखना चाहिए। क्या आप उन्हें भूखे रहने और मरने देंगे ? पिछले चार वर्षों से मेरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है साथ ही भीषण समुद्री तूफान भी आये हैं। पर इन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। उनके लिए ये लाभकारी काम हैं। साथ ही हम लोगों को सस्ता खाना दे रहे हैं। इसलिए वे सभी बहुत खुश हैं। आज आंध्र के हर मजदूर की जेब में कुछ पैसा है।

का जवाब देना शोभा नहीं देता। आज भी वह दुर्व्यवहार कर ही रहे हैं—हर प्रकार का काम तेलुगु देशम सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। यह बहुत मुश्किल काम है और उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तेलुगु देशम सरकार आज लोगों की शक्ति और उनके समर्थन पर टिकी है। किसी एक आदमी की मर्जी पर नहीं।

माया: हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप पूरे आंध्र में घूम रहे हैं?

रामाराव: हां, मैं घूम रहा हूं।

माया: फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

रामाराव: बुरी नहीं है। यह तो बहुत खास किस्म की प्रतिक्रिया है। लोग मानते हैं कि इंका चुनाव नहीं जीत सकी, तो अब ये सारे हथकंडे अपना रही है, जिससे तेलुगु देशम सरकार गिरायी जा सके।

माया: क्या आपको यह अंदेशा है कि इंका इस फैसले का उपयोग केन्द्र से आपकी सरकार को बर्खास्त कराने के रूप में कर सकती है?

रामाराव: मुझे नहीं मालूम वे क्या करनेवाले हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, अपने लोगों का फैसला मेरे लिए अधिक बड़ा है और जब तक मुझे उनका समर्थन प्राप्त है, मैं यहां बना रहूंगा।

माया: क्या इंका तेलुगु देशम की नैतिकता पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाकर आपके इस्तीफे की मांग करने के लिए अभियान छेड़ने की योजना बना रही है?

रामाराव: हमारे यहां कोई दोहरापन नहीं है। वे कुछ लोगों और हमारी पार्टी पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, पर इस मामले में लोग ही उन्हें पछाड़ दे रहे हैं। उन्हें १९८४ की बातें याद करने दीजिए।

माया: इंका का कहना है कि दो रुपए किलो चावल और सस्ते दर पर कपड़ा देकर आप सरकारी खजाने के धन को बरबाद कर रहे हैं।

रामाराव: उनके अनुसार ये काम विकास योजना में नहीं आते। उनके लिए विकास वही है जो ३०-४० वर्षों में हो। जल्दी हो जानेवाला कोई काम विकास है ही नहीं। अगर एक गरीब आदमी को चावल, अपनी रोजाना के जरूरत की चीजें सस्ती मिलती हैं, तो वह इसे अपने परिवार में खुशी-खुशी मिल बांटकर खा लेता है। लोकतंत्र को हर आदमी का खयाल रखना चाहिए। क्या आप उन्हें भूखे रहने और मरने देंगे? पिछले चार वर्षों से मेरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है-साथ ही भीषण समुद्री तूफान भी आये हैं। पर इन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। उनके लिए ये लाभकारी काम हैं। साथ ही हम लोगों को सस्ता खाना दे रहे हैं। इसलिए वे सभी बहुत खुश हैं। आज आंध्र के हर मजदूर की जेब में कुछ पैसा है।

माया: उप-चुनावों के परिणाम् तेलुगु देशम के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं?

रामाराव: नहीं, वे काफी संतोषजनक रहे हैं। जब आप प्रतिशत वोट की बात देखते हैं, तो यह तेलुगु देशम के काफी पक्ष में हैं। वायालपाडु की जिस सीट पर इंका को बड़ा नाज था, वहां हमने जीत हासिल की। हमारी पार्टी बहुत गरीब है और हम उन लोगों जैसा पैसा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन तेलुगु देशम को गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त है।

माया: आपकी फिल्म 'विश्वमित्र' का क्या हुआ?

रामाराव : बननेवाली है। पटकथा तैयार हो गयी है।

माया : अब तो सारे देश में आपके दर्शक हो गये हैं। अब यह फिल्म आप सिर्फ तेलुगु में क्यों बना रहे हैं?

रामाराव : यह हिन्दी में भी बनेगी। उसके संवाद भी तैयार हैं। विश्वमित्र के सबसे बड़े पुत्र आंध्र ने ही इस प्रदेश और वंश की स्थापना की, इसीलिए मेरी इस विषय में खास रुचि है। विश्वमित्र के पौत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत है। इस प्रकार विश्वमित्र देश के बाबा और आंध्र प्रदेश के पिता हैं। ऋषि लोग सभी मंत्रों को गुप्त रखते थे। सिर्फ विश्वमित्र ही इस विश्व के परमपिता थे और उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, 'ओम भूर्भुः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्'', वह महापुरुष थे।

इस फिल्म के पहले हिस्से में उनके पुत्र और दूसरे में उनके पौत्र अर्थात दुष्यंत और शकुंतला की कहानी रहेगी। तीसरे हिस्से में त्रिशंकु की कहानो होगी, जिसके लिए विश्वमित्र ने एक स्वर्ग की रचना की थी। इसके बाद हरिश्चंद्र की कहानी होगी जिन्होंने जात-पांत की परवाह न करते हुए सत्य और कर्म का पालन किया। अंतिम हिस्सा राम पर होगा। विश्वमित्र उनके गुरु थे। उन्होंने ही राम को असली योद्धा बनाया। उन्होंने ही ऋषियों को परेशान करनेवाले राक्षसों को खतम करने के लिए उन्हें युद्ध की विद्या सिखायी। ऐसा करने के बाद राम सीता से विवाह करते हैं।

माया : इसका अर्थ हुआ कि तेलुगु लोग भी हिन्दू 'मिथक' का हिस्सा हैं?

रामाराव : हां, हमारा इतिहास यही बताता है। राम अयोध्या में थे, लेकिन वह श्रीलंका तक गये और दक्षिण में भी उनकी पूजा होती है। द्वारिका उत्तर में है, पर भगवान कृष्ण तो वैश्विक हैं। हमारे भगवान वैंकटेश्वर की उत्तर में भी पूजा होती है। इसी तरह हमारी संस्कृति एकदम घुलीमिली है और उसमें स्नेह और भाईचारे के मजबूत बंधन हैं, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता।

माया : दक्षिण के चारों राज्य केन्द्र के हाथ से निकल चुके हैं। अगर केन्द्र में इंका रही, तो उत्तर-दक्षिण का विभाजन होना है, तो क्या आप दक्षिण के अगुवा बनेंगे?

रामाराव : यह चाहे जो हो। महत्व पार्टियों का नहीं है। महत्वपूर्ण है देश। मेरा निजी मत है कि मैं कभी भी ऐसा विभाजन नहीं होने दूंगा। मैं अपने को सबसे पहले भारतीय मानता हूं, उसके बाद ही किसी राज्य का। यह हमारा देश है। कोई दक्षिण भारत और उत्तर भारत नहीं है। हम सभी इसी के वासी हैं।

माया : फिर आप क्यों सोचते हैं कि दक्षिण से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ।

रामाराव : देश में एक पार्टी का शासन हो, तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में असली सहकारिता होनी चाहिए। एक पार्टी के शासन से अनेक हानियां हैं। वही ब्रिटिश शासन पद्धति आज तक चल रही है। वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं। आज भी वोट खरीदा जाता है, क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या इसी के लिए हमारे महान नेताओं ने हमें आजादी दिलवायी? क्या इसी लोकतंत्र की बात हमारे पूर्वज करते रहे हैं?

माया : तमिलनाडु की हाल की घटनाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

रामाराव : तमिलनाडु में जो कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत दुख हुआ, इंका ने वहां बड़ा गंदा खेल खेला है। एकाएक मेरे बंधु, एम०जी० रामचन्द्रन को 'भारत रत्न' देने और तुरंत उनकी पत्नी और पार्टी की सरकार को गिराने का क्या मतलब है? वह तो इंका के दोस्त भी थे। उनकी पार्टी को तो मौका मिलना चाहिए था। गैरइंका दलों से व्यवहार का यह बहुत गंदा तरीका है।

माया : कहा जा रहा है कि जयललिता गुट के समर्थन से मूपनार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर चुनाव हुए, तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा?

रामाराव : यह तो लोगों का फैसला होगा। मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इंका किसी 'ऐरे गैरे' को मुख्यमंत्री बना देती है, तो यह लोगों की भावना के विपरीत होगा। इसी तरह इंका संस्कृति फैलती है।

माया : अन्नाद्रमुक और द्रमुक के बीच मध्यस्थ बनना आपको कैसा लगेगा?

रामाराव : जरूरत पड़ी, तो क्यों नहीं बनूंगा। मैं तो विपक्ष की सारी गैरइंका पार्टियों के मेल के पक्ष में हूं। अगर मुझसे कुछ बनेगा, तो मैं जरूर करूंगा। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि मैं आंध्र से भी अधिक समय तक तमिलनाडु में रहा हूं। ३२० फिल्मों में काम करने के लिए मैं ३५ वर्षों तक मद्रास में रहा हूं। मेरा बेटा बालकृष्ण, जो अभी फिल्मों में खूब चल रहा है, मद्रास में ही है। मद्रास में हमारे कई घर हैं।

माया : आंध्र के अलावा कन्नड़भाषी और तमिल लोगों में भी अपनी लोकप्रियता के सहारे क्या आप तमिलनाडु में राजनीतिक स्थायित्व लाने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं?

रामाराव : सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र की बात ही क्यों? आइये देश की बातें करें। लेकिन बंधु, मैं अपने को राजनीतिज्ञ नहीं मानता। इसलिए आपके सवाल समझ पाना और उनके जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है।

माया : क्या अब तक की अपनी भूमिका से आप संतुष्ट हैं?

रामाराव : संतुष्टि-असंतुष्टि का सवाल ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि सिर्फ कर्म किये जाओ और फल की चिंता मत करो। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। क्या होगा, इसकी चिंता मुझे नहीं है। एक बार मैंने भगवा वस्त्र पहन लिया, तो यह मेरा कर्तव्य है कि अच्छे कर्म ही करूं। भगवा रंग हमारी हिन्दू संस्कृति में सबसे पवित्र रंग है। राणा प्रताप का ध्वज इसी रंग का था। हमारे छत्रपति शिवाजी के ध्वज का रंग भी केसरिया (भगवा) ही था। हमारे महान ऋषियों ने भी सिर्फ केसरिया वस्त्र ही पहने। यह इसकी शुद्धता और पवित्रता को बताता है। यह आपको दुनिया की माया से अलग रखता है।

मैं कहता हूं कि देश में असली सहकारिता होनी चाहिए। एक पार्टी के शासन से अनेक हानियां हैं। वही ब्रिटिश शासन पद्धति आज तक चल रही है। वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं। आज वोट खरीदा जाता है, क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या इसी के लिए हमारे महान नेताओं ने हमें आजादी दिलवायी? क्या इसी लोकतंत्र की बात हमारे पूर्वज करते रहे हैं?

माया : पर आपको नहीं लगता कि राजनीति और भ्रष्टाचार आजकल एक दूसरे के प्रतिरूप हो गये हैं?

रामाराव : राजनीति सेवा का माध्यम है। यह कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं है, जहां लोगों के द्वारा स्थापित आदमी सत्ता और पद को भुना ले।

माया : विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कुछ कर रहे हैं, आपको उसका कुछ भविष्य नजर आ रहा है?

रामाराव: वह राजनीति को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। जैसा मैंने आपको कहा, मैं तो पूरे राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए हूं। मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी में राजनीतिक स्वच्छता आये।

माया: इलाहाबाद का उप-चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर अमिताभ वहां से दुबारा खड़े होकर जीत जाते हैं, तो इंका इसे अब तक के अपने काम पर 'जनता की मोहर' मानेगी। अगर अमिताभ खड़े होते हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए जायेंगे?

रामाराव: मुझे सोचने दीजिए। जैसा मैंने कहा, मैं लोगों का आदमी हूं। अगर मेरी सेवाओं की जरूरत हुई, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।

माया: अमिताभ भी फिल्मी कलाकार हैं, पर उनके खिलाफ कई आरोप हैं?

रामाराव: वह हमारे एक अच्छे कलाकार भाई हैं। उनके खिलाफ लगनेवाले आरोपों पर जनता को ही फैसला करने दें। मैं क्या कह सकता हूं?

> **भिंडरावाले को केंद्र ने चढ़ाया। गोरखालैंड समस्या के साथ भी यही हुआ। देश में ऐसे मुद्दे हों ही क्यों? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी समस्याएं सुलझाये जिससे देश अखंड रहे और कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, जिससे लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। सरकार को चाहिए कि वह समस्याओं को टालने और उसका फायदा उठाने की जगह तुरंत निपटारा कर दे।**

माया: एक राजनेता के रूप में आप उन्हें कैसा मानते हैं?

रामाराव: वह बहुत कम बात करते हैं। इसलिए राजनीति के बारे में उनकी निजी राय मैं नहीं जानता। अगर उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता, तो हम भी जानते कि वह क्या चीज हैं?

माया: आपके कहने का अर्थ है कि राजनीति में उन्होंने कुछ खास नहीं किया?

रामाराव: उन्हें अपनी काबीलियत दिखाने का बहुत मौका नहीं मिला। अगर वह दुबारा खड़े होते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि लोग क्या फैसला देते हैं। जनता को उनके काम पसंद आयें या नहीं।

माया: राजीव सरकार पर अनेक आरोप लगे हैं और विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। क्या यह मांग जायज है?

रामाराव: जरूर ठीक है। उन्हें सामने आकर सफायी देने दीजिए। अगर वह पाक-साफ हैं, तो इसे साबित करें। अगर वह खुले होते और हर बात को सही तरह से साबित करते, तो कोई अविश्वास ही नहीं रहता।

माया: इंका आपके और आपके परिवार के लोगों के खिलाफ अनेक आरोप लगा रही है।

रामाराव: इसीलिए मैंने अग्रवाल जांच आयोग बैठा दिया है। उन्हें एक भी आरोप सही साबित करने दीजिए, मैं खुद को खरा साबित करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई बचाये नहीं। मैं अपनी ईमानदारी और निष्ठा को जानता हूं, इसलिए ऐसी परीक्षा देने से डरता नहीं।

माया: लेकिन आयोग बनने पर भी वे हाईकोर्ट में गये तो?

रामाराव: उन्हें जाने दीजिए। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं।

माया: आपके पारिवारिक मामलों के लिए तो आयोग नहीं है।

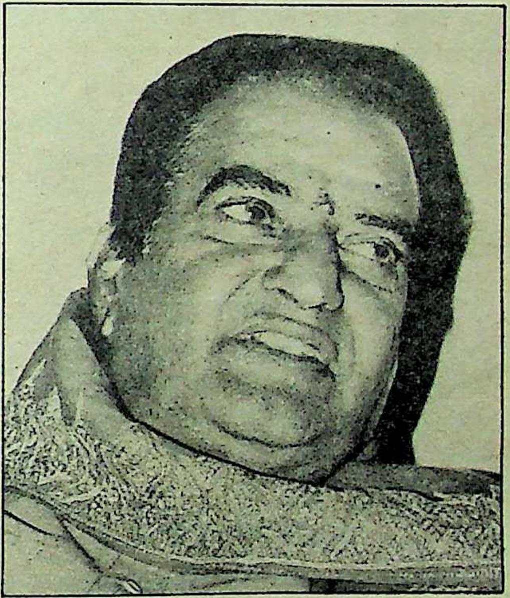

रामाराव: आप क्यों उन बातों को मुझ पर थोप रहे हैं जो सही नहीं हैं। आप मछलीपट्टनम की हैं और मैं नेमीकूल का। हम दोनों एक ही जिले के हैं। अगर कल आपको अपनी योग्यता के कारण भी कुछ मिलता है, तो लोग कहेंगे कि आप मेरे जिले की हैं, इसलिए ऐसा हुआ, यह तो लोगों का दुश्मन है। यह क्या है? क्या यह सही हो सकता है? उन्हें कहने दीजिए। राजनीति में कोई भी गलती करके बच नहीं सकता। मुझे अपने को बचाना-छुपाना नहीं है। मैं तो लोगों का सेवक हूं।

माया: आप कब से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब आप निराश हो गये हैं या और कोशिश करेंगे?

रामाराव: मेरे जीवन में निराशा नहीं है। मुझे अभी भी उम्मीद है।

माया: बालासाहब देवरस बयान दिये जा रहे हैं कि राजीव को बदलने की जरूरत नहीं है।

रामाराव: वह अखंडता को बनाये रखने में असफल रहे हैं। देश में शांति नहीं है। इन चीजों से आप उनकी सफलता-असफलता का खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं त्रिपुरा, प०बंगाल, असम और पंजाब समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार को कसूरवार ठहराता हूं। उन्हें शुरू में ही समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। उन्होंने इन समस्याओं को बढ़ने क्यों दिया?

माया: क्या आपको विपक्षी दलों की सरकारवाले राज्यों की मुश्किलों के लिए केन्द्र दोषी लगता है?

रामाराव: हां, लोग यही कहते हैं। भिंडरावाले को केन्द्र ने चढ़ाया। गोरखालैंड समस्या के साथ भी यही हुआ। देश में ऐसे मुद्दे हों ही क्यों? केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वह ऐसी समस्याएं सुलझाये जिससे देश अखंड रहे और कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, जिससे लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। सरकार को चाहिए कि वह समस्याओं को टालने और उसका फायदा उठाने की जगह तुरंत निपटारा कर दे। उसने जानकी रामचन्द्रन के साथ पहले समर्थन देने और बाद में वापस लेने का फरेब क्यों किया?

माया: एमजीआर को भारत रत्न देने की कई लोगों ने आलोचना की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

रामाराव: यह उन सभी लोगों के साथ होगा जो केन्द्र से बढ़िया रिश्ते रखते हैं। मुझे लगता है कि एक कलाकार की हैसियत से और केन्द्र के साथ रहनेवाले राजनेता होने के कारण वह इसके हकदार थे। जब वह जिंदा थे, तो मुझे नंबी (छोटा भाई) कहकर पुकारते थे।

माया: क्या श्रीमती गांधी के बाद केन्द्र-राज्य संबंध और बिगड़े हैं?

रामाराव: हां, निश्चित रूप से बिगड़े हैं। अगर पैसे का सही आवंटन और सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता है, तो संबंध और बिगड़ेंगे। राज्यों को मातृभाषा को बढ़ावा देने और पढ़ाने का हक नहीं है। इन चीजों में हस्तक्षेप का क्या मतलब है? हम उद्योग तो बिना हस्तक्षेप के लगा सकते हैं, पर यह क्यों नहीं? वे उपदेश क्यों देते रहते हैं? क्या महात्मा गांधी ने यही रास्ता बताया था?

माया: क्या आंध्र के मामलों पर प्रधानमंत्री आपसे राय-मशविरा करते हैं?

रामाराव: अब नहीं। अब तो हमारी योजनाएं भी मंजूर नहीं होतीं।

माया: हरियाणा चुनाव के समय आपने वहां का दौरा किया था। तेलुगु नहीं जानने वाली जनता को अपनी बात बताने में आपको कैसा महसूस होता था?

रामाराव: मुझे हरियाणा के लोगों से काफी स्नेह मिला। वे मुझे और फिल्मों में अभिनीत मेरी मिथकीय भूमिकाओं को जानते हैं। वे बहुत भले और अच्छे लोग हैं।

माया : आप बड़े धार्मिक लगते हैं। आप किस देवता की पूजा करते हैं?

रामाराव : भगवान वेंकटेश्वर हमारे पारिवारिक देव हैं। लेकिन मैं सभी भगवानों की पूजा करता हूं। मैं अन्य धर्मों का भी आदर करता हूं।

माया : क्या आप नियमित पूजा करते हैं?

रामाराव : नहीं, मैं पूजा नहीं करता, बल्कि अपने अंदर मौजूद भगवान की प्रार्थना करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर मौजूद भगवान मेरी आत्मा ही है। मैं बड़े सवेरे दो बजे उठता हूं। चार बजे से मैं ध्यान शुरू करता हूं। एक घंटे तक ध्यान करता हूं। मैं अपनी चेतना और सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। मैं भगवान या अच्छी बातों पर ध्यान केन्द्रित करता हूं। मैंने देखा है कि इससे मेरी हर मुश्किल दूर हो जाती है।

माया : आंध्र और खासकर हैदराबाद की सांप्रदायिक स्थिति कैसी है?

रामाराव : कहीं कोई तनाव नहीं है। सभी जगह शांति और भाईचारा है।

माया : हाईकोर्ट के स्तर पर कड़वाहट का अनुभव कर चुकने के बाद क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है?

रामाराव : इस बात पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? देखें क्या होता है?

माया : हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या न्यायपालिका के प्रति लोगों के नजरिए में कोई बदलाव आया है?

रामाराव : मैं न्यायपालिका के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मुझे सिर्फ अपने बारे में चिंता है कि क्या मैं लोगों का विश्वास पाने लायक हूं या नहीं।

माया : आपके खिलाफ यह आरोप भी है कि आपके परिवार के कई लोग तेलुगु देशम पार्टी में हैं। क्या लोगों ने इस पर कोई आपत्ति की है?

रामाराव : सबसे पहले मुझे यह कहने दीजिए कि मेरा कोई बेटा पार्टी में नहीं है। मेरे सात बेटे और तीन बेटियां हैं और इनमें से कोई भी पार्टी में नहीं है। उनकी आपत्ति मेरे दामादों को लेकर है। इनमें से एक, चंद्र बाबू नायडू मेरे राजनीति में उतरने के पहले से ही राजनीति में था। वह इंका में था। वह तेलुगु देशम की नीतियों से प्रभावित था और इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन मैंने उसे दाखिला नहीं दिया। मैंने तीन लोगों की कमेटी बनायी, जिसमें श्रीनिवासुलु रेड्डी भी थे, जो अब पार्टी में नहीं हैं। इस कमेटी ने कहा कि पार्टी के विकास, उसमें अनुशासन लाने और उसके दिशा देने में चन्द्र बाबू की सेवाओं की जरूरत है। मेरे दूसरे दामाद डा० वेंकटेश्वर राव की डाक्टरी खूब चल रही थी, पर इसके बावजूद पार्टी के गठन के साथ ही उसने यह काम छोड़कर मेरा साथ देने का फैसला किया। लोगों ने उसे अपना विधायक चुना, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं लोगों की इच्छा के विपरीत कैसे काम करूं? जब मैंने काफी कमाईवाला फिल्मी जीवन छोड़ा, तो मेरा उद्देश्य लोगों की सेवा करना था, किसी एक आदमी का हित साधना नहीं। ये आरोप मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लगाये जाते हैं।

माया : क्या आपके भूतपूर्व राजस्वमंत्री श्रीनिवासुलु रेड्डी इंका के हथकंडों के शिकार हुए?

रामाराव : मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लोगों को खुद फैसला करने दीजिए। मेरे मन में किसी के लिए बुरे विचार नहीं हैं।

माया : प्रधानमंत्री द्वारा जिलाधिकारियों से मिलने-जुलने के बारे में आपकी क्या राय है?

रामाराव : वह जायें और बड़े शौक से उनसे मिलें, लेकिन इसे नीति या सिद्धांत न बनालें। इन यात्राओं के दौरान स्थानीय आई०ए०एस० अधिकारी ही उन्हें सारे विवरण देते रहे हैं। वह सिर्फ जिलाधिकारियों को ही क्यों चुन रहे हैं? वे लोग जिले को बुनियादी इकाई बनाने की सोच रहे हैं। अभी ही राज्य सरकारों के अनेक अधिकार ले लिये गये हैं और उन्हें भिखमंगा बना दिया गया है। हर छोटी-छोटी बात के लिए हमें दिल्ली दरबार में आकर सलामी बजानी होती है और अपनी योजनाएं मंजूर करानी होती हैं। राज्य सरकारों की परवाह कौन करता है? आई०ए०एस० अधिकारी तो आपके ही हैं। उनके लिए मौका निकालकर मिलने जाने की क्या बात है। मंशा सही भी हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें भी तो हैं। वह हमें जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और हम देखेंगे कि सारा काम ठीक से चले। वह ऐसा नजरिया क्यों अपना रहे हैं?

> राज्य सरकारों के अनेक अधिकार ले लिये गये हैं और उन्हें भिखमंगा बना दिया गया है। हर छोटी-छोटी बात के लिए हमें दिल्ली दरबार में आकर सलामी बजानी होती है और अपनी योजनाएं मंजूर करानी होती हैं। राज्य सरकारों की परवाह कौन करता है? आई०ए०एस० अधिकारी तो आपके ही हैं। उनके लिए मौका निकालकर मिलने जाने की क्या बात है। मंशा सही भी हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें भी तो हैं। वह हमें जिम्मेवारी सौंप सकते हैं और हम देखेंगे कि सारा काम ठीक से चले।

माया : आपको इसके पीछे क्या मंशा लगता है?

रामाराव : मैं उनकी सोच का आधार नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन जो भी हो, मैं मानता हूं कि वह (राजीव गांधी) राज्यों को बहुत कमजोर और बेचारा बना रहे हैं।

माया : लेकिन वह भोपाल में जिलाधिकारियों से मिल चुके हैं जो इंका शासित राज्य है?

रामाराव : वह आंध्र में भी १३, १४, १५ और १६ फरवरी को उनसे मिले। वह वहां भी यह अभियान चलाना चाहते हैं। वह जब हैदराबाद आते हैं, तो मैं पांच आई०ए०एस० अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहता हूं। उन्हें भी यह बात समझ आ जानी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। वह राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं।

माया : आंध्र की नक्सल समस्या के बारे में आप क्या योजना बना रहे हैं?

रामाराव : केन्द्र की ही कोई नीति नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? वैसे नक्सलियों को लोगों का समर्थन नही है और ऐसा मेरी पार्टी के वनवासी कल्याण कार्यक्रमों के कारण हुआ है। एक दिन में हमने अदिलाबाद में एक हजार वनवासी लड़कों को नौकरी दी, जहां नक्सली सक्रिय हैं और इस वनवासी इलाके की ५० फीसदी नौकरियां वनवासियों के लिए ही आरक्षित हैं। नौजवानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जानेवाला है, जिससे वे लोग आत्मरक्षा कर सकें।

माया : क्या १९८३ की तरह अब भी आपको लोगों का स्नेह प्राप्त है?

रामाराव : मुझे ऐसा ही लगता है। यह बात अनेक उपचुनावों, पंचायत और मंडल चुनावों से स्पष्ट है जो १९८३ के बाद हुए हैं। २१ जिला परिषदों में से १८ में हमें जीत हासिल हुई। मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं लोगों के समर्थन पर ही टिका हूं और मैं समाज के लिए कभी बोझ नही बनूंगा।

माया : राजीव सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद भी क्या आपको उनसे अच्छे काम की उम्मीद है?

रामाराव : मेरी एक ही इच्छा है कि देश से गरीबी खतम हो जाये। पर आप खुद देश की हालत देख सकती हैं। यही जवाब है।

माया : इतनी लोकप्रियता पाने के बाद क्या आप केन्द्र में अपने को राजीव का विकल्प मानते हैं?

रामाराव : मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मान सकता। मैं भाग्य में विश्वास करता हूं। मैं अपने लिए कोई चीज, कोई पद नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि लोगों की सेवा कर सकूं।

—विजय दत्त, पद्मा शास्त्री

ई०सी०एल०

कोयला उद्योग चौपट

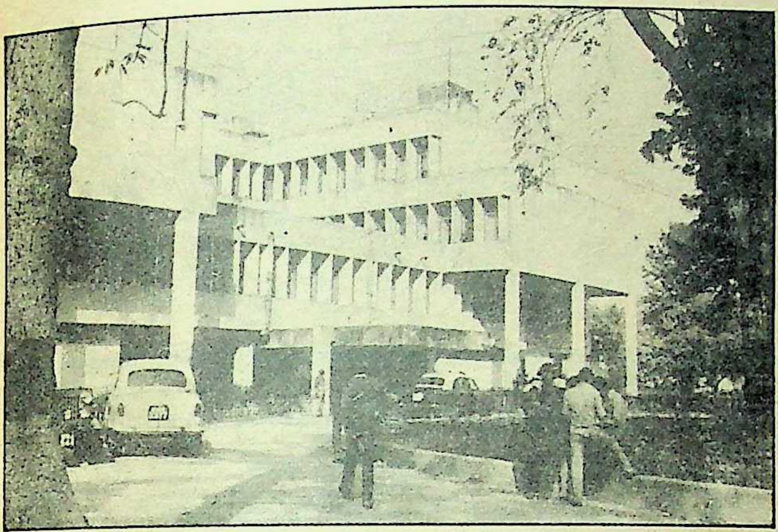

कुव्यवस्था का केंद्र: ई०सी०एल० का मुख्यालय

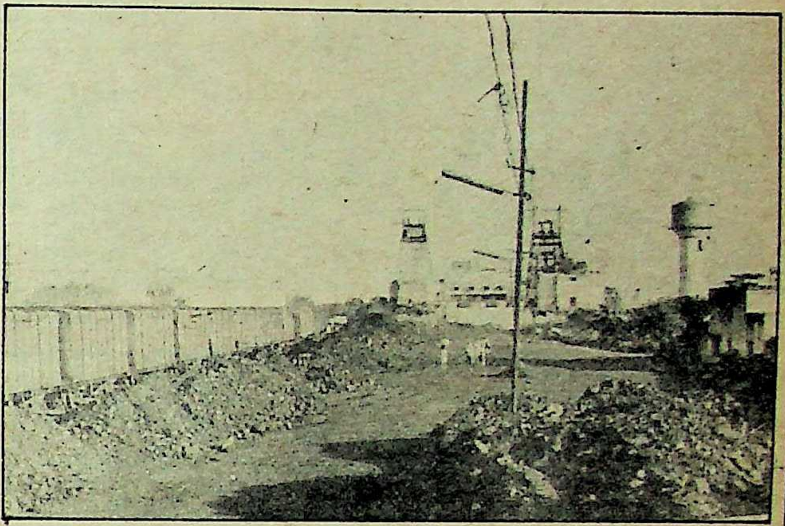

बेवजह बर्बादी: आसनसोल स्थित कोयला खान

कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और देश में इसके विशाल भंडार हैं, लेकिन कोयले के दाम दिनदूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। इस असंगत मूल्यवृद्धि के लिए 'ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' को दोषी बताया जाता है। क्या ई०सी०एल० संगठन भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था का केंद्र बन गया है?

देश में कोयले का विशाल भंडार है। फिर भी चक्रवृद्धि दर से कोयले का दाम बढ़ाने में कोल इंडिया की जो शाखा मुख्य भूमिका निभा रही है, उसका नाम है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ई०सी०एल०। दाम के हिसाब से सचमुच कोयला आज काला हीरा, यानी ब्लैक डायमंड है। जानकार लोगों की राय में कोल इंडिया की विभिन्न शाखाएं यदि सामान्य रूप से कोयले का उत्पादन बढ़ाती जायें, तो भी ई०सी०एल० की मौजूदा कार्य-पद्धति के कारण निकट भविष्य में कोयला दुर्लभ हो सकता है।

व्यापक भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए के अपव्यय, आर्थिक ढांचे पर ध्यान न देने, बिना सरकार की स्वीकृति के परियोजनाएं शुरू करने, विभिन्न परियोजनाओं का काम अधर में लटका कर उन पर होनेवाले व्यय को २०-२५ गुना बढ़ा देने और ठेकेदारों के आगे आत्म-समर्पण करने में ई०सी०एल० शायद विश्व रिकार्ड कायम करेगा। भ्रष्टाचार इतना व्यापक है और इसकी जड़ें इतनी गहरी और फैली हुई हैं कि सारी कथा लिखने पर छोटा-मोटा ग्रंथ बन जायेगा। इस बात को ध्यान में रखकर यहां भ्रष्टाचार के कुछ खास पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार या कोयला मंत्रालय यह सब नहीं जानता। संसद की 'पब्लिक अकाउंट्स कमेटी', 'कमेटी आफ पब्लिक अंडरटेकिंग' या केंद्र सरकार के आडिट विभाग ने इस संबंध में बार-बार टीका-टिप्पणी की है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और पुराना रवैया बदस्तूर चालू है। इस कारण कोल इंडिया के जन्मकाल १९७४ से १९७७ तक कोयले का औसत वार्षिक उत्पादन २ करोड़ ३० लाख टन के पास ठहरा रहा।

१९७१ में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मोहन कुमारमंगलम ने जो तर्क दिये थे, वे हैं: (१) निजी क्षेत्र के खान मालिकों ने अगली पीढ़ियों के लिए कोयले को बचाये रखने की आवश्यकता की पूरी उपेक्षा की है। (२) उपभोक्ताओं के हित की चरम उपेक्षा करते हुए केवल अधिकाधिक मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया गया। (३) सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दो क्षेत्र हैं—लौह और विद्युत। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला उद्योग का विकास आवश्यक है। लेकिन निजी क्षेत्र के खान मालिक इस दिशा में काफी पूंजी निवेश करने से कतराते हैं।

क्या ई०सी०एल० उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी को पूरा कर पाया है?

जन्मकाल से भ्रष्टाचार की छूट: शुरू से ई०सी०एल० को मानो भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली हुई है। यदि कहा जाये कि ई०सी०एल० का गठन ही अवैध हुआ है, तो लोग जरूर चौंक पड़ेंगे। लेकिन यह मनगढ़ंत बात नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यभार को कम करने और कोयला उद्योग का विस्तार करने के लिए १ नवंबर, १९७५ को ई०सी०एल० का गठन हुआ। लेकिन स्वतंत्र प्रतिष्ठान के रूप में ई०सी०एल० के लिए क्या कानूनी प्रावधान होंगे, या इसके पास संपत्ति और दायित्व क्या रहेंगे, इसका निर्णय १९८७ में भी नहीं हुआ। इस संबंध में कोल इंडिया के प्रवक्ता से पूछा गया, तो उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि 'कमेटी आफ अंडरटेकिंग' ने जो कड़ी टिप्पणी की है, उसे काटने की क्षमता उसमें नहीं है। 'कमेटी आफ अंडरटेकिंग' का कहना है: "कमेटी को यह जानकर अचंभा हुआ है कि कंपनी के संस्थापन के १२ वर्ष बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड से ई०सी०एल० को परिसंपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण की वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं।" यानी स्वतंत्र स्वामित्व सिद्ध करने के लिए ई०सी०एल० के पास कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज नहीं हैं। दूसरी तरफ ई०सी०एल० कारण बता रहा है: "मिल्कीयतनामे की अनुपलब्धता...किन्हीं कारणों से पुराने मालिकों ने इसे केंद्रीय सरकार को नहीं सौंपा" लेकिन ये कारण क्या हैं, इस संबंध में कोयला उद्योग से मतलब रखनेवाला हर विभाग जबान पर ताला लगाये हुए है। यह बात कुछ ऐसी हुई कि इम्तहान तो दूंगा, लेकिन प्रवेश-पत्र साथ में नहीं रखूंगा। कोई लापरवाह परीक्षार्थी भले ही ऐसा कह सकता है, लेकिन केंद्र सरकार का एक बृहत प्रतिष्ठान भी ऐसा कहेगा, उम्मीद नहीं की जा सकती।

संभवत: अपना 'टाइटिल डीड'

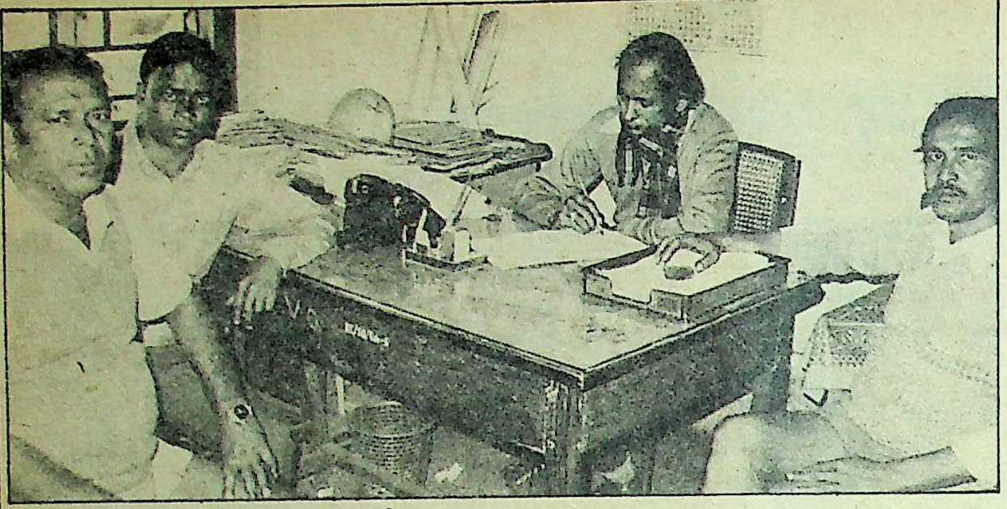

हेराफेरी: चुआरडी कोयला खान का कार्यालय

(मिल्कीयतनामा) न होने के कारण यह प्रतिष्ठान तानाशाह, बेफिक्र और फिजूलखर्च बन गया है। इस संबंध में 'कमेटी आफ अंडरटेकिंग' की टिप्पणी है: "इस संबंध में कोयला विभाग और नियंत्रक कंपनी सी०आई०एल० ने जो कारण दिये हैं, उनसे समिति संतुष्ट नहीं है।"

किसी कंपनी की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर उसके लिए बैंक से अथवा धन विनियोजक किसी संस्था से ऋण लेना संभव नहीं होता। ई०सी०एल० के साथ वही हो रहा है। ई०सी०एस० को कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऋण लेना पड़ता है। यानी, अपनी शाहखर्ची से कोल इंडिया को दिवालिया बना देने पर भी ई०सी०एल० पर कोई आंच नहीं आ सकती। फिर जनता की जेब काटकर चक्रवृद्धि दर से कोयले का दाम बढ़ाकर घाटे को पूरा किया जा रहा है। इसलिए विनियोजन बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन ज्यों का त्यों है। जन्मकाल से अब तक १२-१३ वर्षों में ई०सी०एल० का उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन खर्च २०-२५ गुना बढ़ चुका है। इस सदर्भ में ई०सी०एल० के वार्षिक उत्पादन (देखिए रेखाचित्र) से ई०सी०एल० के विकास की गतिशीलता का आसानी से पता चल जाता है। १९८६-८७ में ई०सी०एल० ने दो करोड़ ३० लाख टन के आसपास कोयले का उत्पादन किया। कोल इंडिया के अधीन अन्य पांच कंपनियों द्वारा १९८६-८७ में जहां लगभग १५ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, वहां ई०सी०एल० का योगदान मात्र दो करोड़ ३० लाख टन रहा। इसके विपरीत वेस्ट बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड का १९८६ के पहले उत्पादन एक करोड़ १० लाख २६ हजार टन था, लेकिन उसने एक साल (८६-८७) में ५ करोड़ टन कर लिया। जहां तक घाटे का सवाल है ई०सी०एल० ने अपने जन्मकाल से अब तक कभी लाभ का मुंह नहीं देखा है। (देखिए रेखाचित्र)।

लचर कामकाज: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों ने इस कंपनी के बनने के बाद से कई ऊलजलूल काम किये हैं। उर्जा मंत्रालय या कोल बोर्ड की स्वीकृति के बिना अनेक परियोजनाएं शुरू करने के प्रयास में करोड़ों रुपए बर्बाद किये गये हैं। जिन क्षेत्रों में कोयला है, उन क्षेत्रों में खनन न कर, उन क्षेत्रों में खनन किया गया, जहां कोयला नहीं है। 'कमेटी आफ पब्लिक अंडरटेकिंग' की राय में हर संभव ऋण पाने के बावजूद उसका सदुपयोग नहीं हुआ। १९७५-७६ में जहां हर 'मैन. शिफ्ट' में ०.५६ टन कोयले का उत्पादन हुआ था, वहीं १९८५-८६ में ०.५२ टन हुआ।

ई०सी०एल० के सूत्रों से पता चला, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रतिष्ठान ने १९८२-८३ में मध्यम और लघु स्तरीय ३३ परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया। इनमें १६ परियोजनाएं नयी थीं, तो १७ परियोजनाओं को नये सिरे से शुरू करना था। हर परियोजना के लिए २ करोड़ रुपए से ५ करोड़ रुपए तक अनुमानित व्यय का प्रावधान था। खोजबीन से पता चला कि इतने दिनों बाद सिर्फ ३ परियोजनाओं का काम पूरा हुआ है। अधिकांश परियोजनाओं का काम या तो फाइलों में बंद है या फिर 'अनिवार्य कारण' से रुका हुआ है। यानी, जो काम समय से करने पर २ करोड़ रुपए में पूरा होता, अब उसके लिए ८-१० करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त और चार बड़ी परियोजनाएं साल भर पहले शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। काम न होने का कारण अज्ञात है। इन परियोजनाओं पर अब ४०.८ प्रतिशत खर्च बढ़ गया है (देखिए तालिका)।

मनमानी: बिना 'सर्वे' और फिजीबिलिटी (व्यवहार्यता) रिपोर्ट और बिना कोल बोर्ड की स्वीकृति के काम करना ई०सी०एल० के लिए सामान्य बात है। १९७१ में ई०सी०एल० ने एक बृहत परियोजना को हाथ में लिया। उसका नाम है महावीर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। इस परियोजना को शुरू करने से पहले यह पता नहीं लगाया गया कि यहां कोयला मिलेगा या नहीं और न कोल बोर्ड या ऊर्जा मंत्रालय से स्वीकृति ली गयी। फिर इधर-उधर बहुत मिट्टी उलटने-पलटने के बाद ई०सी०एल० को लगा कि यहां कोयला नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक इस काम में १८२ करोड़ ८० लाख रुपए खर्च हो गये थे। इस मामले में 'जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया' ने क्या भूमिका निभायी, यह सवाल किया जा सकता है।

व्यय वृद्धि

परियोजना का नाम	अनुमानित व्यय (करोड़ रु० में)	अब संशोधित व्यय (करोड़ रु० में)	कितने वर्षों की देर हुई
चीनाकुड़ी	८.४३	४५.५४	८
धेमोमानी	११.९ ९.०६	७३.७६	८
अमृतनगर	१०.८५	६५.४५	८
कुनुसुतोरिया	३.४८	१९.४९	८
राजमहल	४७.८३	११७.२५	४
कुल	१३१.२०	३२१.४९	

इसी प्रकार कोल बोर्ड की स्वीकृति के बिना और भी ४ छोटी परियोजनाओं पर २-२, ३-३ करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं। ये परियोजनाएं हैं: कालिदासपुर (२ करोड़ ७४ लाख ४५ हजार रुपए), केस्टा (१३ लाख ८६ हजार रुपए), कोटादिही (२ करोड़ ५५ लाख ४९ हजार रुपए) और अडंमान (२ करोड़ ३४ लाख ८७ हजार रुपए)। इसके अलावा खनन में परेशानी होने पर केंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को २ करोड़ ४० लाख रुपए खर्च करने के बाद त्याग दिया गया।

जरूरी कागजात गायब: ई०सी०एल० को १९७५ और १९८२ के बीच १४ बड़े कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली। निर्देश था कि समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा की जायेगी और आनुषंगिक व्यय कितना बढ़ा, उसका पता लगाया जायेगा। लेकिन दीर्घसूत्रता के कारण १४ में से ९ प्लांट लग ही नहीं सके। इस संबंध में ई०सी०एल० का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या, प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव और नौकरी पाने के लिए स्थानीय युवकों

द्वारा प्रदर्शन आदि कारणों से काम शुरू नहीं किया जा सका। इस विलंब के कारण अनुमानित खर्च ६ लाख रुपए बढ़ गया। फिर जिस धेमोमानी कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए एक करोड़ १८ लाख रुपए का प्रावधान था, उसके जरूरी कागजात गायब हो गये। गायब होने का पता भी अधिकारियों को दो वर्ष बाद चला। इस संबंध में केंद्र सरकार का आडिट विभाग (सी०ऐंड ए०जी० रिपोर्ट में) अगर कड़ी टिप्पणी न करता, तो शायद यह मामला कभी प्रकाश में न आता।

बेवजह नुकसान : कोल बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि स्टाक यार्ड में कोयला तीन हफ्ते से अधिक समय तक न रखा जाये। लेकिन यह नहीं लगा कि ई०सी०एल० इस निर्देश पर विशेष ध्यान देता है। स्टाक यार्ड में अधिक समय तक कोयला पड़े रहने से धूप, पानी और धूल-गर्द से उसके स्तर में गिरावट आती है। इससे तापीय बिजलीघरों और अन्य कई उद्योगों के उत्पादन में व्यवधान पड़ता है। १९७५-७६ में ई०सी०एल० के स्टाक यार्ड में कोयला तीन हफ्ते रखा रहता था जो १९८४-८५ में १०.९ हफ्ते और इस समय ११ हफ्ते से अधिक हो गया है। अधिक समय तक कोयला खुले में पड़े रहने के कारण उसकी चोरी भी बढ़ गयी है। १९८३-८४ में ६० लाख रुपए के कोयले की चोरी हुई थी जो इस समय लगभग ७० लाख रुपए की हो गयी है।

ई०सी०एस० की सफायी: इस संबंध में ई०सी०एल० का कहना है कि समय से रेलवे के रेक न मिलने से मजबूर होकर कोयले को स्टाक यार्ड में रखना पड़ता है। अगर यह तर्क सही है, तो १९८५-८६ में ई०सी०एल० ने रेलवे को हर्जाने के रूप में एक करोड़ ४२ लाख रुपए का डेमरेज चार्ज क्यों दिया? सिर नहीं तो सिरदर्द कैसा! अगर रेलवे के काम में हर्ज नहीं किया, तो हर्जाना क्यों देना पड़ा? इसलिए लगता है कि रेलवे रेक न मिलने की बात करना महज बहाना है।

मेहनत का दुरुपयोग: कोयला खान-मजदूर

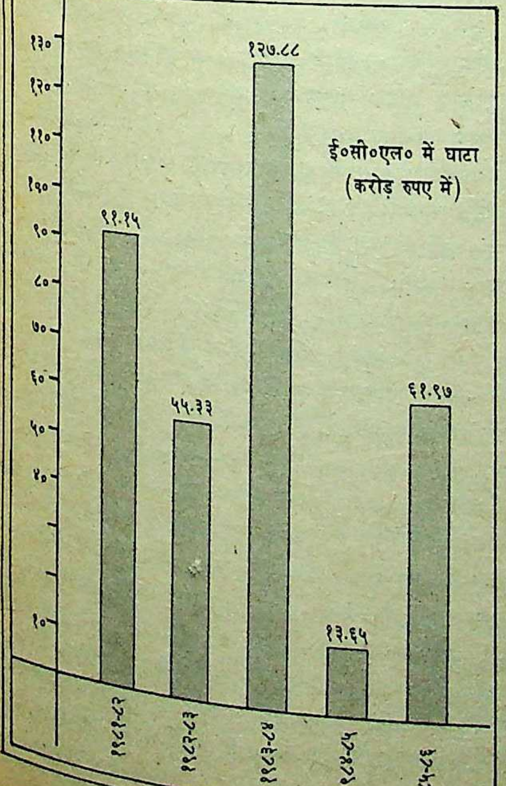

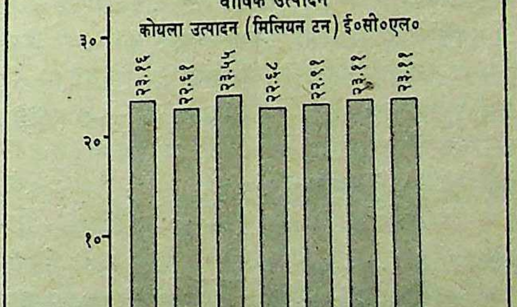

१९८५-८६ में ई०सी०एल० ने बैंडेल तापीय विद्युत केंद्र को ११ लाख ६१ हजार टन कोयला दिया। इसमें थोड़ा-सा कोयला बी०सी०सी०एल० का भी था। उस कोयले से दो अरब, ३७ करोड़ ८० लाख यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। दूसरी तरफ उसी अवधि में संथालडीह तापीय विद्युत केंद्र में एक अरब १६ करोड़ ८० लाख यूनिट विद्युत उत्पादन के लिए ७ लाख ४० हजार टन कोयला खर्च हुआ। इस अनुपात को देखने से पता चलता है कि संथालडीह विद्युत केंद्र में कोयले की जो खपत होनी चाहिए थी उससे एक लाख टन अधिक हुई। यानी, जहां लगभग ६ लाख टन कोयला लगना चाहिए था, वहां ७ लाख ४० हजार टन कोयला लगा। कोयले के स्तर के कारण ऐसा हुआ या हिसाब में गड़बड़ी के कारण, यह तो वही बता पायेंगे, जिन्होंने कोयले की आपूर्ति की है। लेकिन विभिन्न विद्युत केंद्रों से यह शिकायत मिल रही है कि खराब कोयले के कारण विद्युत उत्पादन में बाधा पड़ रही है। सही ढंग से विद्युत उत्पादन न होने से जो नुकसान होना है, वह तो हो ही रहा है, ऊपर से संथालडीह तापीय विद्युत केंद्र को हर साल मुफ्त में ६ करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने पड़ रहे हैं।

ताबड़तोड़ खनन: ई०सी०एल० का कार्यक्षेत्र आसनसोल परगना है। इस परगने के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों ने शिकायत की है कि कोयला निकालने के लिए जहां-तहां ताबड़तोड़ खनन कार्य हुआ है, लेकिन ई०सी०एल० ने सैंड फिलिंग कर उन स्थानों को नहीं पाटा जिससे अनेक इलाके खतरनाक बन गये हैं। वहां आग लगने या जमीन धसकने का खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। रानीगंज और सिउड़ी रोड के आसपास काफी जमीन धसक चुकी है। ई०सी०एल० के अंतर्गत इस समय कोयला खान क्षेत्र १५५० वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में १३ शहरी बस्तियां और ३६१ ग्रामीण बस्तियां हैं। इनकी आबादी लगभग २० लाख है। कोयला खनन के कारण जियोलाजिकल सर्वे ने अभी से ७० गांवों को खतरनाक मान लिया है। इन बस्तियों में बराकर, कुलटी, रानीगंज, आसनसोल, साकतोड़िया और जामूरिया आदि हैं। गत ६ जनवरी को ही राजपुर कोलियरी में धसकन से ३ महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में सीटू (सी०आई०टी०यू०) के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक हाराधन राय ने साफ शब्दों में कहा कि जिन खानों में काम बंद हो चुका है, उनको बालू से भरने की जिम्मेदारी जे०एल० रोप नामक कंपनी की है। इस प्रतिष्ठान ने १९७८ में ३४ लाख टन बालू भरने का काम किया जो अब घटकर २० लाख टन हो गयी है। अधिकांश काम ठेकेदारों के जिम्मे हैं, जिसमें अधिकारी मदद कर रहे हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कई ठेकेदारों के नाम भी गिनाये, जैसे एस० उपाध्याय, बलराम दे और मदन लाल भलेटिया आदि।

श्री राय ने यह भी शिकायत की कि कई वर्षों से ई०सी०एल० कोयला निकालने के लिए टनेल प्रणाली का (जिसमें खंभे छोड़ने पड़ते हैं) उपयोग न कर ओपन कास्ट माइनिंग पर जोर दे रहा है। इससे कोयले का स्तर गिर रहा है। टनेल प्रणाली द्वारा कोयला निकालने पर ऊपर की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ओपन कास्ट प्रणाली से बड़े-बड़े जलाशय बन रहे हैं, जिससे हजारों लोग विस्थापित होने लगे हैं।

खनन की ओपन कास्ट प्रणाली पर अधिक जोर दिये जाने के कारण ई०सी०एल० कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा था। कोयला निकालने की अवैज्ञानिक प्रणाली होने के कारण इसमें बहुत सारा बढ़िया कोयला खंभों के रूप में भूगर्भ में छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत ओपन कास्ट प्रणाली में कोयले का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसके गुण में कमी आ गयी है। भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अब भी बिहार और पश्चिम बंगाल की खानों से अधिक मात्रा में अच्छा कोयला मिलता है। इसका कारण है अंडरग्राउंड माइनिंग।

शिकायत मिल रही है कि विभिन्न खानों में (जहां अंडरग्राउंड माइनिंग चालू थी) बड़ी मात्रा में कोयला रहते हुए भी ई०सी०एल० निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। काम बंद कर उन खानों को अनुपयोगी घोषित किया जा रहा है। जैसे, प्योरमामला कोलियरी की नं० १ और नं० २ खानों में अब भी जो कोयला है, उसका परिमाण कई लाख टन होगा। आगामी अप्रैल-मई तक आराम से उन खानों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ई०सी०एल०-ने वहां खनन कार्य रोक दिया है। प्योरमामला कोलियरी के कई किलोमीटर के अंदर बनग्राम क्षेत्र की खान में २५०० खंभे मौजूद हैं, जिनसे दो-तीन वर्षों के लिए ३-४ लाख टन कोयला मिल सकता है। प्योरमामला क्षेत्र के एक निवासी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, "काम की खानों को बेकार घोषित करना अब ई०सी०एल० के लिए फैशन बन गया है। अब उसका ओपन कास्ट माइनिंग में अधिक आग्रह है। लेकिन लाखों रुपए का कोयला बरबाद किया जा रहा है।"

ठेकेदार-प्रेम: आसनसोल क्षेत्र के एक ट्रेड यूनियन नेता ने शिकायत की कि समय के साथ-साथ ई०सी०एल० का ठेकेदार-प्रेम बढ़ता जा रहा है। खानों में बालू भरने के काम में अब ठेकेदारों की प्रमुख भूमिका है। रेलगाड़ी या ट्रक में कोयला लदान के काम में ठेकेदार के मजदूरों को लगाया जा रहा है। निश्चित अवधि के बाद कुछ समय के लिए काम से बिठाकर या दूसरी जगह (जहां एक मजदूर के लिए जाना संभव नहीं होता) तबादले की व्यवस्था कर ई०सी०एल० ने ऐसा पक्का इंतजाम कर लिया है जिससे ठेके के श्रमिकों की स्थायी नियुक्ति न हो सके। ऐसे कई हजार ठेके के श्रमिक हैं जो १०-१२ वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी अस्थायी हैं। कोयला उठाने के काम में ई०सी०एल० अनेक स्थानों पर अपनी मशीनों आदि का उपयोग न कर ठेकेदारों की मशीनों आदि का उपयोग कर रहा है। १९८२-८३ में इस तरह ई०सी०एल० ने ४५ करोड़ ३३ लाख रुपए की अपनी मशीनें खड़ी रखी थीं। इस समय ऐसी मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है (सी० ऐंड ए०जी० रिपोर्ट)। इस तरह मशीनें किराये पर लेने से एक तरफ खर्च बढ़ा है, तो दूसरी तरफ बेकार पड़ी मशीनों की कार्यक्षमता नष्ट होती जा रही है।

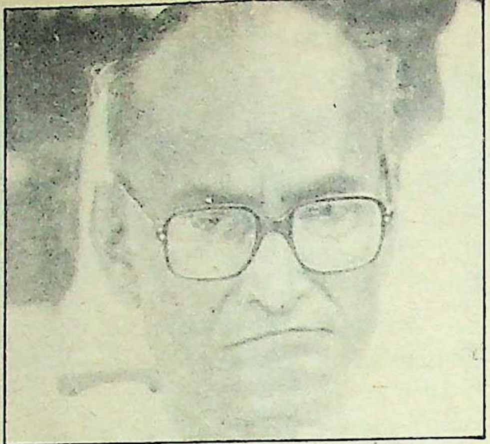

जांच के आदेश: भूमि राजस्वमंत्री विनय चौधरी

इस समय हमारे देश में कोयले का जो भंडार है, उससे आसानी से दो-तीन सौ वर्षों तक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए अकारण कोयले के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ प्रयत्नशील होने और ईमानदार बनने की।

मुआवजा नहीं: पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को बराबर यह शिकायत मिल रही है कि कोयला खानों के विस्तार के लिए ई०सी०एल० हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन बदले में जमीन मालिकों को एक पैसा मुआवजा नहीं दे रहा है। कई वर्ष पहले स्थानीय ट्रेड यूनियन नेताओं के सामने ई०सी०एल० के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि कोयला खानों के विस्तार के लिए जिनकी जमीन ली जायेगी उनको समुचित मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त हर एक एकड़ कृषि भूमि या हर दो एकड़ अकृषि भूमि के लिए संबंधित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी। लेकिन ई०सी०एल० में पहले से ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। उनकी संख्या को कम करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से निर्देश आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा आश्वासन दिया था, इसका कारण ई०सी०एल० अधिकारी ही जानते होंगे।

इसके कुछ दिन बाद ई०सी०एल० के अधिकारी दिये गये आश्वासन से पीछे हटने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि दो एकड़ कृषिभूमि या तीन एकड़ अकृषिभूमि के अधिग्रहण पर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों ने कहा, नौकरी-चाकरी देना संभव नहीं है। ली गयी जमीन के बदले उसके पूर्व स्वामियों को रुपया दिया जायेगा। इस मामले में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर दिल्ली को सूचित किया। बार-बार प्रयास करने के बावजूद वह न तो भुक्तभोगियों को नौकरी दिला सके और न मुआवजे की रकम। ऐसे एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र के युवकों को नौकरी देने के लिए कोल इंडिया को बाध्य किया था। हां, इसके लिये न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था (लालचंद मारतो ऐंड अदर्स वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड ऐंड अदर्स, सी०एम०पी० न० १६ ३३१ आफ १९८२)। कोल इंडिया एक जगह उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेगा, तो दूसरी जगह क्यों नहीं करेगा?

सरकारी जमीन पर कब्जा करने और लीज की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उस जमीन का उपयोग करते रहने के बारे में भी ई०सी०एल० के विरुद्ध शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के भूमि एवं भूराजस्व मंत्री विनय चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले ऐसे एक मामले में अपने विभाग के अधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने पर निजी क्षेत्र की खानों का स्वामित्व केंद्र सरकार को मिल गया। इस तरह अधिग्रहीत अनेक खानें बहुत दिनों से बंद पड़ी हैं, लेकिन उनकी जमीन को ई०सी०एल० वाम मोर्चा सरकार को नहीं लौटा रहा है। राष्ट्रीयकरण से पहले इन भूखंडों के जो स्वामी थे, उनके पास भी अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए वैध कागज-पत्र नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कानून के मुताबिक ये भूखंड नजूल के रूप में राज्य सरकार को वापस मिलने चाहिए, लेकिन ई०सी०एल० की इसमें कोई रुचि नहीं दिखायी देती। पश्चिम बंगाल के भूमि एवं भूराजस्व मंत्री विनय चौधरी ने ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों को जांच करने का आदेश दिया है। इस तरह की २१ कोयला खानें हैं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की थोड़ी सी समीक्षा कर लेने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस उद्देश्य से कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसको ई०सी०एल० कितना पूरा कर सका है? इसका जवाब पाने के लिए देश में कोयला उद्योग के विकास की दर का विवेचन करने पर निराशाजनक चित्र देखने को मिलेगा। इसमें भी ई०सी०एल० ने प्रमुख भूमिका निभायी है। ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइज ने कुछ समय पहले जो पुस्तिका प्रकाशित की है, उसमें बताया गया है कि १९८५-८६ के वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों ने ११९९ करोड़ ३५ लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। यदि कुछ उद्योगों में अधिक हानि न होती, तो लाभ की यह मात्रा बढ़ती। जिन उद्योगों में हानि हुई है, उनमें सबसे पहले कोयला उद्योग का नाम लिया गया है।

इस समय हमारे देश में कोयले का जो भंडार है, उससे आसानी से दो-तीन सौ वर्षों तक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए अकारण कोयले के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ प्रयत्नशील होने और ईमानदार बनने की। आज देश में विदेश से अनेक वस्तुओं का आयात हो रहा है। इससे हम धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय बाजार से हटने लगे हैं। यदि प्रयत्नशीलता और ईमानदारी का आयात संभव होता, तो हम वह भी करते। लेकिन वह संभव नहीं है, तो आत्मसमीक्षा के बाद निष्ठा के साथ काम शुरू करना उचित होगा। अब भी सुधार लाने का समय है, नहीं तो राष्ट्रीयकरण भी निरर्थक हो जायेगा।

—चंदन नियोगी

SIVE ADMINISTRATION
10-1 DECEMBER 1987
PRIME MINISTER

प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी रोकने का वादा : भोपाल में जिलाधिकारियों की बैठक में मोतीलाल वोरा, राजीव गांधी और पी० चिदंबरम

प्रधानमंत्री-जिलाधिकारी बैठक

मकसद क्या है ?

पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश भर के जिलाधिकारियों से सीधी मुलाकात का अभियान शुरू कर रखा है। इस अभियान के तहत उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर में, उ०प्र० के भोपाल में म०प्र० के और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के जिलाधिकारियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रशासन से राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करने का वादा किया। सवाल उठता है कि क्या ऐसा संभव है? एक प्रश्न यह भी है कि गैरइंकाई राज्यों में उनका यह अभियान कहीं प्रदेश सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप तो नहीं है?

हाल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिलाधिकारियों से मिलने का जो अभियान शुरू किया, वह अधिकारियों के लिए सूरज के पश्चिम में उदय होने जैसा आश्चर्य था। लेकिन गैर इंकाई मुख्यमंत्रियों ने इसे अपने क्षेत्र में सीधा दखल और प्रशासनिक अधिकारियों पर उनके नियंत्रण को खतम करने के लिए शुरू किया गया प्रयास माना है। आलोचनाओं की परवाह न करते हुए राजीव गांधी अपनी बैठकें जारी रखे हुए हैं। गोरखपुर व भोपाल के बाद उन्होंने एक और बैठक हैदराबाद में की है। यह बैठकें प्रत्यक्षत: विकास कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करने के लिए और जिलाधिकारियों पर राजनीतिक दबाव खतम करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें देश की मौजूदा प्रणाली की रीढ़ मानते हैं।

क्या वह जिला प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव खतम करने में कामयाब हो सकेंगे या इन बैठकों से अंत में जिलाधिकारी केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र बन कर रह जायेंगे?

पिछले दिसंबर में भोपाल में आयोजित प्रशासनिक कार्यशाला में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा सिर्फ उद्घाटन समारोह में ही उपस्थित थे, जब प्रधानमंत्री ने

८०

जिलाधिकारियों को संबोधित किया। उसके बाद श्री गांधी ने जिलाधिकारियों के साथ जो बैठकें कीं, उनमें श्री वोरा उपस्थित नहीं थे। गैरकांग्रेस-इ मुख्यमंत्रियों से ऐसी छूट देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वास्तव में एन०टी० रामाराव तो पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, "जिलाधिकारी केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वह सीधे केंद्र से बातचीत करने की जगह हमें प्रशासन के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी दे।" वह यह भी कहते हैं, "केंद्र ने राज्यों के अधिकांश अधिकार पहले ही छीन लिये हैं और आज राज्य सरकारें भिखमंगी बन गयी हैं।" लेकिन राजीव गांधी जोर देकर कहते हैं, "यदि प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन नहीं किये गये, तो देश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।" प्रत्यक्षतः वह जिला स्तर पर हुए प्रशासनिक क्षरण से परिचित हैं जोकि व्यवस्था की कमजोरी का एक प्रमुख कारण भी है।

> **एक समय था जब जिलाधिकारी संदेह से परे था। वह जिले की समस्याओं का सबसे ईमानदार निर्णायक माना जाता था। एक समय जिलाधिकारी रह चुके आर०के० कौल अपने जमाने की याद करते हुए कहते हैं कि कोई भी उग्र ग्रामीण जिलाधिकारी से मिलकर ठंडा हो जाता था। यदि उसकी समस्या सुलझ गयी, तो इसके लिए श्रेय जिलाधिकारी को मिलता था, लेकिन यदि नहीं सुलझी, तो भी वह संतुष्ट रहता था और कहता था, "कलक्टर साहब ने तो कोशिश की, पर भगवान को ही मंजूर नहीं था।"**

इसीलिए वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिला स्तर पर हो रहे विकास कार्यों पर नजर रखने के लिए दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले सुपर कंप्यूटर को 'फीड' करने में जिलाधिकारी 'की बोर्ड' की भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार सलाह-मशविरे में सभी ४३६ जिलाधिकारियों की भागीदारी चाहती है, क्योंकि उसकी धारणा है कि उनसे जो फीडबैक मिल सकती थी, वह राज्य प्रशासन के उच्चाधिकारी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष सूचनाएं चाहती है जिससे कि 'उचित अनुवर्ती कदम उठाये जा सकें।' प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक का एक कारण यह भी बताया जा रहा है।

बदतर स्थिति : लेकिन आलोचकों को इसमें संदेह नजर आता है। वे सोचते हैं कि इससे निश्चित रूप से केंद्रीयकरण होगा जिससे स्थिति और खराब होगी, क्योंकि पार्टी के हित के लिए लोग पहले से ही सक्रिय हैं। एक वरिष्ठ नौकरशाह जो तीन जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं, कहते हैं, "पार्टी के हितों के शामिल हो जाने से प्रधानमंत्री के लिए लोगों पर अंकुश रख पाना कठिन हो जायेगा। अधिकांश समय जिलाधिकारी पार्टी के नेताओं के अवांछित कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे उनसे असामाजिक तत्वों को बंदूकों के लाइसेंस या राशन कार्ड यह कर कर दिलाये जाते हैं कि वे वोट बैंक बनाने में मदद करेंगे।

हालांकि कुछ जिलाधिकारी ऐसे भी हैं जो अनुचित आदेशों का पालन नहीं करते। बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार के समय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद और उद्योगमंत्री इंदूदीप सिन्हा ने बरौनी के तत्कालीन जिलाधिकारी यशवंत सिन्हा को जो अब जनता पार्टी के महामंत्री हैं, सर्किट हाउस में इसलिए फटकारा था, क्योंकि वह उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे थे जिनकी जमीन ताप बिजलीघर और खाद कारखाने के लिए अधिग्रहीत की गयी थी। सिन्हा ने उन लोगों के सामने जिनमें कुछ जाने-माने असामाजिक लोग थे, इस तरह फटकारने का विरोध भी किया और इस पर भी जब उद्योगमंत्री अपनी जिद पर अड़े रहे, तो जिलाधिकारी कमरे से बाहर चले गये। उन्होंने केंद्र में वापस भेज देने के आग्रह के साथ तत्काल अपना इस्तीफा दे दिया।

आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम०जी० रामचंद्रन ने जिलाधिकारियों को आदेश दे रखा था कि जब भी जयललिता उनके जिले में पहुंचें, वे जिले की सीमा पर उनका स्वागत किया करें। यही कारण है कि जिलाधिकारियों ने अपना आत्मबल और विश्वास खो दिया है, जिसकी कि प्रशासन चलाने में जरूरत पड़ती है। लेकिन एक समय था जब जिलाधिकारी संदेह से परे था। वह जिले की समस्याओं का सबसे ईमानदार निर्णायक माना जाता था। ऐक समय जिलाधिकारी रह चुके आर०के० कौल अपने जमाने की याद करते हुए कहते हैं कि कोई भी उग्र ग्रामीण जिलाधिकारी से मिलकर ठंडा हो जाता था। यदि उसकी समस्या सुलझ गयी, तो इसके लिए श्रेय जिलाधिकारी को मिलता था, लेकिन यदि नहीं सुलझी, तो भी वह संतुष्ट रहता था और कहता था, "कलक्टर साहब ने तो कोशिश की, पर भगवान को ही मंजूर नहीं था।" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थितियां बदलने लगीं। लेफ्टिनेंट जनरल जे०एस० अरोड़ा को १९४८ के कश्मीर आपरेशन से लौटते समय की एक मजाकिया घटना की याद ताजा है। उनकी यूनिट का सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया था। पहली बार उन्होंने देखा कि एक डी०एम० जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की खुशामद में लगा था और अध्यक्ष महोदय जिनके मोजे बुरी तरह फटे हुए थे, अध्यक्ष कम मसखरे

राजीव गांधी ने जिलाधिकारियों से कहा...

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गत दिसंबर में भोपाल में आयोजित तीन दिन की कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिला प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी की चर्चा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को आश्वस्त किया कि दिये गये कार्यक्रमों का ईमानदारी से क्रियान्वयन करनेवालों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि वे संकीर्णता में लिप्त निहित स्वार्थी तत्वों, संकुचित निष्ठा और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से बचें। उन्होंने प्रशासन को गति देने वाले उपायों पर विचार-विमर्श किया और उन्हें जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर किये जाने वाले सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की जानकारी दी। उन्होंने जनता के व्यापक हितों और आधुनिकीकरण पर भी विशेष जोर दिया जो उनके अनुसार आवश्यक तो हैं, लेकिन सुरुचिता में बदलाव की कीमत पर नहीं, क्योंकि इससे भारतीयता की भावना को बनाने में मदद मिलेगी।

इसके बाद कार्यशाला में शामिल ८० जिलाधिकारियों को आठ समूहों में बांटकर विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। जैसे समाज के नाजुक समूहों और उनकी आवश्यकता को किस तरह पता लगाकर उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जाये? जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जिला स्तर पर कैसे विभिन्न सरकारी विभागों में तालमेल रखा जाये? तालमेल की सुविधा के लिए कैसे शीर्ष संबंध हैं, लोगों की शिकायतों पर कैसे ध्यान देकर उन्हें दूर किया जाये? सरकारी एजेंसी और निर्वाचित प्रतिनिधियों में कैसे संबंध हैं, देश के कुछ जिलों में अहमदनगर पद्धति पर की गयी नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा और अधिकार हस्तांतरण और प्रक्रिया में परिवर्तन।

कार्यशाला में कंप्यूटर आधारित जिला सूचना प्रणाली की कार्यपद्धति दिखायी गयी जो अगले ६ महीने में प्रमुख योजनाओं पर नजर रखने के लिए आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रह करेगी। इसे इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने विकसित किया है।

राजीव गांधी ने कुल मिलाकर जिला प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।

—नवनीत सरकार

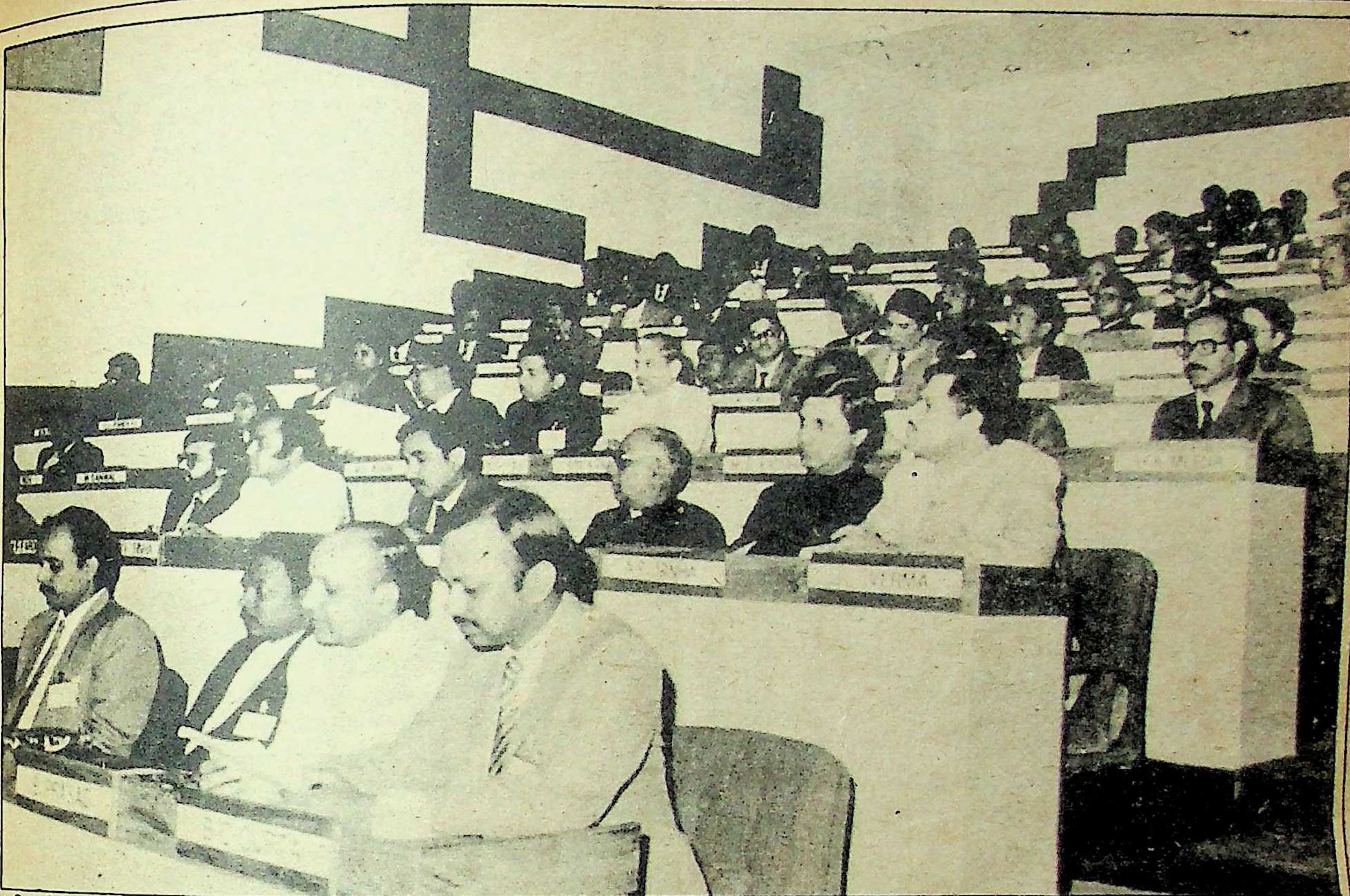

छवि और अधिकार की वापसी ? : भोपाल सम्मेलन में म०प्र० के जिलाधिकारी

अधिक लग रहे थे। समय जैसे-जैसे और गुजरा जिलाधिकारियों की स्थिति और स्तर और गिर गया। जिसका परिणाम यह हुआ—जनरल अरोड़ा के शब्दों में, "आज जिलाधिकारियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और उनसे हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।" के०आर० मलकानी इसके आगे कहते हैं, "अब तो हर जिले में नौकरशाहों को निर्देशित करने और केंद्र को सूचित करने के लिए फोतेदारों की कमी नहीं है।"

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से बैठकें करने का जो प्रयास शुरू किया है, वह उत्साहवर्धक है। ऐसा एक संयुक्त सचिव का कहना है जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में जिलाधिकारी रह चुके हैं। यदि प्रधानमंत्री प्रशासन में राजनीतिक दखल रोकने का वचन दें और उसे वास्तविकता में बदल सकें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

उठते सवाल: बहरहाल, यहां यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या अच्छे प्रशासन के लिए प्रशासक ही जिम्मेदार है। भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी के महानिदेशक डाक्टर ईश्वर दास के अनुसार, "इसके लिए सिर्फ प्रशासकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन नौकरशाहों, राज़नीतिज्ञों और जनता के सहयोग से चलता है। प्रमुख समस्या मूल्यों के संकट की है जो आज व्यक्ति-सापेक्ष हो गयी है। इसलिए आज इसमें सुधार के लिए सम्यक प्रयास की जरूरत है, क्योंकि सबको अपनी भूमिका निभानी है।" एक नौकरशाह होने के कारण वह इससे अधिक और कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन असलियत यह है कि राजनीतिज्ञ अब भी गंदा काम किये जा रहे हैं। बस गनीमत इतनी है कि जिला प्रशासन पर असामाजिक तत्वों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजनीतिज्ञ दबाव नहीं डालते। केंद्र के एक सचिव का कहना है, "जिले के विधायक और मंत्री जिलाधिकारियों को राजनीतिक अनुग्रह के लिए आदेश देते रहते हैं। वह संरक्षण और नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की ओर नहीं देखता। इससे प्रशासनिक ढांचे की जड़ें कमजोर हो गयी हैं।"

आर०के० कौल उस घटना को याद करते हैं जब वह मेरठ के जिलाधिकारी थे और उन्होंने विश्वास और चतुराई से अप्रिय घटना होने से बचा ली थी। वह यह भी कहते हैं कि उन पर कोई राजनीतिक और दूसरी तरह का दबाव नहीं डाला गया था। जब इसराइल में मस्जिद-ए-अक्सा पर हमला किया था, तो पूरा अरब समुदाय इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ था। श्रीमती गांधी ने इसराइल के इस व्यवहार की कटु निंदा की थी। भारत के मुसलमान भी इससे क्षुब्ध हो उठे थे और मेरठ के मुसलमानों ने विरोध-जुलूस निकालने का निश्चय किया। इस पर पुलिस अधिकारियों ने

> असलियत यह है कि राजनीतिक अब भी गंदा काम किये जा रह हैं। बस गनीमत इतनी है कि जिला प्रशासन पर असामाजिक तत्वों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजनीतिज्ञ दबाव नहीं डालते। केंद्र के एक सचिव का कहना है, "जिले के विधायक और मंत्री जिलाधिकारियों को राजनीतिक अनुग्रह के लिए आदेश देते रहते हैं। वह संरक्षण और नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की ओर नहीं देखता। इससे प्रशासनिक ढांचे की जड़ें कमजोर हो गयी हैं।"

सोचा कि आर०एस०एस० परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। कौल ने सोचा कि जिस घटना की निंदा प्रधानमंत्री कर चुका हो, उसके खिलाफ जुलूस निकालने की अनुमति न देना राष्ट्रीय नीति के खिलाफ बात हो सकती थी। उन्होंने यही बात कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं से कही, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के कुछ उग्रनेता भी थे। उन्होंने कहा कि वह जुलूस लेकर जिला कचहरी के कंपाउंड तक लायें और इसके लिए उन्होंने ट्रक मुहैया करने का वादा भी किया। वहां उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की उनकी भावनाओं के साथ सहानुभूति है। इस तरह सब कुछ शांतिपूर्ण बीत गया।

एक और आई०एस०एस० अधिकारी भी, जो खुद ज़िलाधिकारी रह चुके हैं, इसी तरह की दूरदर्शितापूर्ण घटना की याद दिलाते हैं। उन्हें आर०एस०एस० के संघचालक ने अपनी बेटी के विवाह में आमंत्रित किया थां। उन्हें विवाह में जाने में संकोच हो रहा था, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया था कि हाल के दंगों के पीछे आर०एस०एस० का हाथ था। फिर भी वह इस विचार से कि वहां कुछ मिनट ही रुकेंगे, विवाह समारोह में गये। लेकिन वहां एक राज्यमंत्री भी मिल गये और वह दो घंटे रुक गये। उसके थोड़े दिनों बाद ही १९७१ के चुनावों के दौरान यह सोचा गया कि आर०एस०एस० उपद्रव कर सकता है, तो डी०एम० ने आर०एस०एस० के प्रधान को टेलीफोन कर कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह चुनाव निर्विघ्न पूरे हो गये। वह जिलाधिकारी इस समय अतिरिक्त सचिव हैं और उनकी धारणा है कि प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से जो बैठकें करने का निर्णय किया है, उससे उनकी पहले की स्थिति और विश्वास लौटेगा, इसलिए इस कदम का सिर्फ समर्थन ही नहीं, अपितु प्रशंसा भी की जानी चाहिए।

श्री गांधी के कदम का स्वागत करते हुए अधिकांश नौकरशाह कहते हैं, "अब जबकि हमें सर्वोच्च नीति-निर्माता से मिलने का मौका मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे प्रशासन में राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी कम होगी और कलेक्टरों की पुरानी छवि और अधिकार वापस होने में मदद मिलेगी। संक्षेप में वे प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वह सत्ता के दलालों और बिचौलियों से बचें। लेकिन यदि वह अपनी पार्टी में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो क्या नौकरशाही में ऐसा कर पायेंगे?

—नयी दिल्ली से पद्मा शास्त्री और भोपाल से नवनीत सरकार

जिलाधिकारियों का मनोबल भर बढ़ेगा

साक्षात्कार/**महेश एन० बुच**

महेश एन० बुच आईएएस अफसर थे। उन्होंने यह तथाकथित स्वर्गिक नौकरी २८ साल तक की। वह अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने कैंब्रिज तथा प्रिंस्टन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर प्रस्तुत हैं, उनके विचार:

माया: प्रधानमंत्री ने प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी रोकने का आश्वासन दिया है। क्या ऐसा संभव है?

बुच: दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार यह नहीं जानते कि प्रशासन तंत्र कैसे काम करता है। प्रधानमंत्री का जिलाधिकारियों से मिलना उनका मनोबल बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।

माया: क्या गैरकांग्रेस-इ शासित राज्य प्रधानमंत्री के कदम को आम लोगों की मदद के रूप में स्वीकार करेंगे?

बुच: क्यों नहीं? आखिरकार मुख्यमंत्री जनता के कल्याण के संरक्षक के रूप में चुने जाते हैं। यदि इससे कोई सुधार होता है, तो उसका प्रभाव राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर भी तो पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में गैरकांग्रेस-इ सेवा मानी जाती है, क्योंकि वहां राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है।

माया: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या धारणा है?

बुच: देश में कई प्रशिक्षण चल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं जानती कि वह किसे प्रशिक्षण दे रही है और क्यों दे रही है, सिर्फ सैनिक प्रणाली में प्रशिक्षण को छोड़कर जहां लोगों का एक समूह एक विशेष क्षेत्र में सर्वाधिक निपुणता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

—नवनीत सरकार

श्री गांधी के कदम का स्वागत करते हुए अधिकांश नौकरशाह कहते हैं, "अब जबकि हमें सर्वोच्च नीति-निर्माता से मिलने का मौका मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे प्रशासन में राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी कम होगी और कलेक्टरों की पुरानी छवि और अधिकार वापस होने में मदद मिलेगी। संक्षेप में वे प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वह सत्ता के दलालों और बिचौलियों से बचें। लेकिन यदि वह अपनी पार्टी में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो क्या नौकरशाही में ऐसा कर पायेंगे?

उत्थान एवं पतन

वारेन हेस्टिंग्स ने १४ मई, १७७२ को कलेक्टर का पद सृजित कर जिला प्रशासन की समेकित प्रणाली की स्थापना की थी। प्रारंभ में कलेक्टर की जिम्मेदारी जिले के राजस्व की वसूली और भूमि विवादों को निपटाना मात्र थी। बाद में भूमि संबंधी दावों को तय करने के लिए उसे न्यायिक अधिकार दिये गये और वह जिला मजिस्ट्रेट कहा जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भी जिला प्रशासन की यह ब्रिटिश परंपरा जारी रखी गयी जो शासन की सर्वाधिक नवीन और प्रभावी प्रणाली मानी गयी।

अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी सरकार के लिए प्रमुख संरक्षक और जनता का अभिभावक हो गया। वह किसी एक विभाग का नहीं, अपितु पूरी सरकार का प्रतिनिधि होता था। स्वतंत्रता के बाद अपनी स्थिति, प्रभाव और अधिकार के कारण वह सामाजिक-आर्थिक प्रगति का प्रभावी उपकरण बन गया। इससे राजस्व वसूली और मजिस्ट्रेटी भूमिका के अलावा उसकी जिम्मेदारी सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान देने की भी हो गयी। इस परिवर्तन की प्रायः यह कहकर आलोचना की जाती रही कि इससे जिलाधिकारी राजनीतिक दबाव की गिरफ्त में आ जायेंगे, जिससे उनकी निष्पक्षता की छवि प्रभावित होगी और लोगों का उनमें से विश्वास खतम हो जायेगा।

स्वतंत्र भारत में सरकार के संघीय ढांचे में जिलाधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के नियंत्रण में आ गया। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें सत्तारूढ़ रहती हैं, तो वह दलीय राजनीति का शिकार हो जाता है।

आज की स्थिति में जिलाधिकारी के अधिकार बहुत कम कर दिये गये हैं।

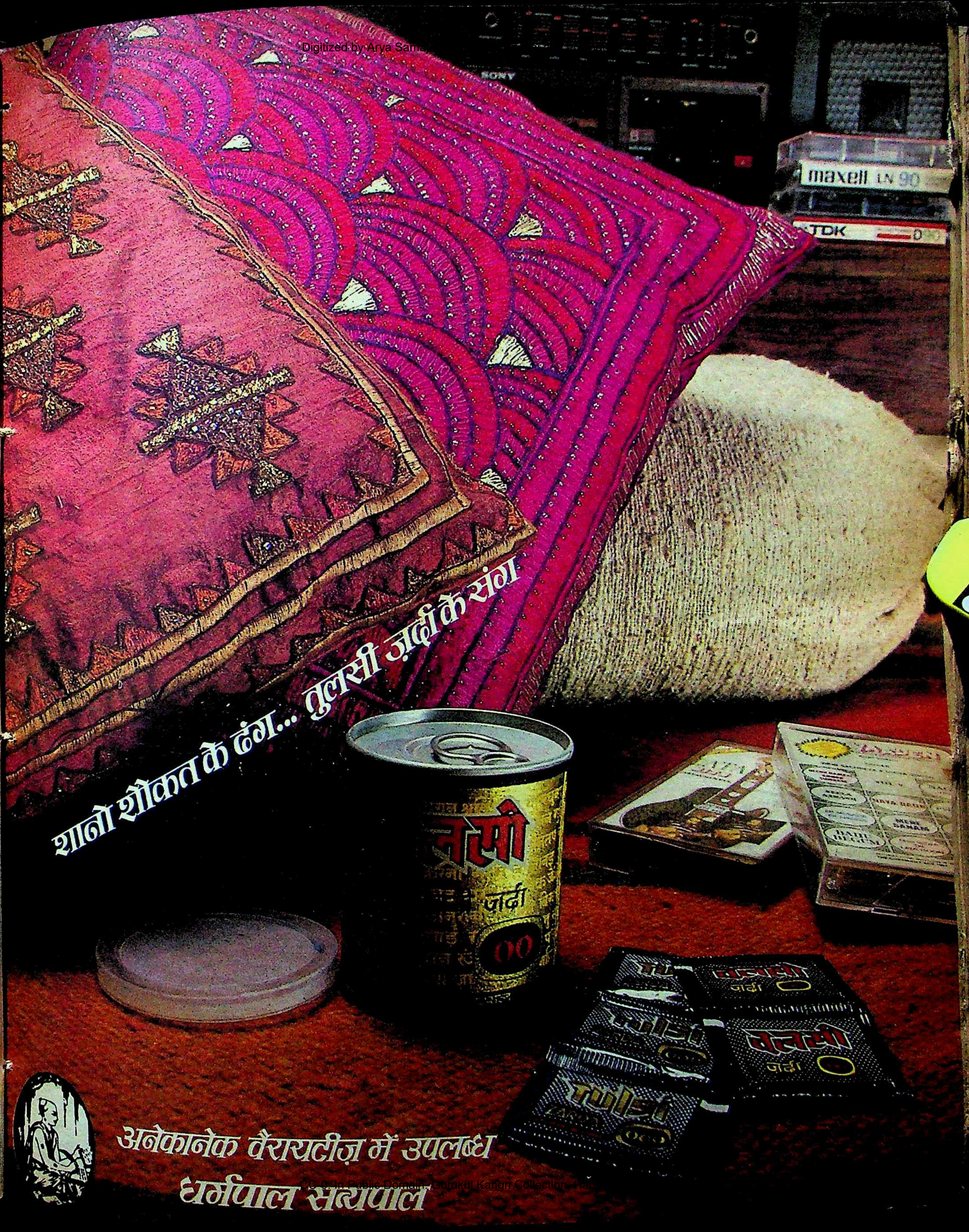
शानो शौकत के ढंग... तुलसी ज़र्दा के संग
तुलसी
ज़र्दा
00
अनेकानेक वैरायटीज़ में उपलब्ध
धर्मपाल सत्यपाल

राज्यों और केंद्र में फेरबदल

किस लिए ?

बहुमत विरोध में: शिवचरण माथुर

वफादारी का फिर इम्तहान: अर्जुन सिंह

छाया: सुनील सक्सेना

आधी रात में दिल्ली से वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा राजीव गांधी के नुमाइंदों को उड़ा कर भोपाल और पटना ले जाने, जितने मिले उतने विधायकों को बिस्तरों से खींचकर चुनाव की रस्मअदायगी करने और फिर पौ फटने के पहले ही नये मुख्यमंत्रियों को झटपट शपथ दिला देने में वे सारे तत्व मौजूद हैं जो वर्चस्व प्रदर्शन के लिए आतुर किसी नेता की तखतापलट कार्रवाई में होते हैं। लेकिन भोपाल और पटना के रोमांचक तमाशे के बाद राष्ट्रपति भवन के लकदक करते अशोक हाल में नये केंद्रीय मंत्रियों के शपथ-समारोह के समय कुछ दूसरा ही नजारा सामने आया। अपने कार्यकाल के अड़तीसवें महीने में जब कुल मिलाकर तेईसवीं बार राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल को फेंट कर, जो नयी 'प्रतिभाएं' पेश कीं, उनसे लगा कि वर्चस्व का प्रदर्शन भले ही किया गया हो, लेकिन असलियत कुछ और है। १९८५ में जो राजीव गांधी योग्यता, स्वच्छता और जवानी को तरजीह देते थे, १९८८ में अब वही राजीव गांधी जातपांत और तबकों को खुश करने की पारंपरिक राजनीतिक शैली पर उतरने के लिए बाध्य हो गये हैं। भोपाल, पटना, जयपुर तथा दिल्ली में हुए हेरफेर का आधार और औचित्य क्या है? क्या इससे पार्टी और राजीव की छवि निखर सकेगी? क्या इन परिवर्तनों के बाद मुंह बाये खड़ी चुनौतियों का वह कारगर ढंग से सामना कर सकेंगे? दिल्ली से विजय दत्त, **भोपाल से** सुधीर सक्सेना, **पटना से** विकास कुमार झा **और जयपुर से** ओम सैनी **की रिपोर्ट:**

राजीव गांधी को आम चुनाव की चिंता कुतरने लगी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में नये मुख्यमंत्री जड़ने और केंद्रीय सरकार में नये मंत्रियों को लादने तथा कुछ मंत्रियों को उलट-पलट करने के पीछे मुख्यतया इसी चिंता का दबाव रहा है। लेकिन इस चिंता से निजात तभी पायी जा सकती है, जब पार्टी पर उनकी पूरी तरह से धाक हो। गौरतलब बात है कि मंत्रिमंडल को बड़े स्तर पर फेंटने के चौबीस घंटों के भीतर ही उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि एक बार मंत्रिमंडल को फिर से फेंटा जायेगा। बड़े स्तर पर राजीव गांधी अब तक तेरह बार और कुल मिलाकर तेईस बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुके हैं और ४७ से बढ़ाकर अपने मंत्रियों की संख्या ६० कर ली है। सैंतीस महीने में इतनी बार अदल-बदल करने वाले शायद वह विश्व में पहले शासनाध्यक्ष हैं। लेकिन तुरंत ही उन्हें चौबीसवें पुनर्गठन की घोषणा क्यों करनी पड़ी? क्या उनको यह डर है कि अब तक जो कांग्रेसी उनके इशारे पर नाचते थे, अब सत्ता का कौर न मिलने के कारण गर्क होते बेड़े के चूहों की तरह भागने की फिराक में हैं?

राजीव गांधी की यह बात सही है कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बारे में पिछले कई सप्ताहों से सोच-विचार हो रहा था। लेकिन जिस हड़बड़ी में इस योजना को लागू किया गया, उससे साफ जाहिर

होता है कि राजीव गांधी पार्टी के गुटों को सक्रिय होने का समय नहीं देना चाहते थे। हालांकि यह मालूम था कि संसद का सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल का पुनर्गठन निश्चित है, लेकिन इसकी जानकारी बूटा सिंह के सिवा किसी को नहीं थी। संभावित दावेदार इंतजार कर रहे थे, कुल्हाड़ी गिरने के डर से मंत्री चुप्पी साधे बैठे थे और सांसद अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पक्ष और विपक्ष में पैरवी करने में मशगूल थे। इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में कोई टंगड़ी नहीं मार पाया। लेकिन प्रधानमंत्री का सचिवालय कुछ समय से काम में जुटा था।

स्मरणीय है कि दिल्ली के चुनावों और संसदीय उपचुनावों के बारे में निर्णय होने के पहले, विश्वसनीय राजनीतिक सलाहकारों और वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों को हिंदी क्षेत्र के मतदाताओं की थाह लेने के काम में लगा दिया गया था। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के फेरे लगाकर डीआईजी स्तर के खुफिया अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि यदि तुरंत आम चुनाव कराये जाते हैं, तो सत्तारूढ़ दल का लोकसभा की ८० प्रतिशत सीटों पर कब्जा निश्चित है। यह निष्कर्ष लिखित में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस अधिकारी ने मौखिक रूप से कुछ लोगों को बता दिया था कि पार्टी की लोकप्रियता रसातल में पहुंच रही है और २५ प्रतिशत स्थान जीतना भी मुश्किल है। शायद इस जायजे और अन्य एजेंसियों की ऐसी ही धारणा ने राजीव गांधी को बाध्य कर दिया कि वह तुरंत कोई निर्णायक कदम उठायें।

आंतरिक कलह: उपर्युक्त तीनों राज्यों में आंतरिक कलह भी साफ दिखायी पड़ रहा थां। बिहार में जगन्नाथ मिश्र सरेआम बिंदेश्वरी दुबे की कब्र खोदने में लगे थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मोतीलाल वोरा के पीछे पड़े थे और राजस्थान में अशोक गहलोत-शिवचरण माथुर-जगन्नाथ पहाड़िया की तिकड़ी हरिदेव जोशी की खटिया खड़ी करने पर तुली थी। इन दुरभिसंधियों से न केवल पार्टी की बधिया बैठ रही थी, बल्कि प्रशासन का भी भट्ठा बैठ रहा था। साथ ही जनमोर्चा के पाले में कूदने की ताक में बैठे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी।

पहला वार हरिदेव जोशी की गरदन पर हुआ। कान फूंकने में माहिर लोगों ने अनेक किस्सों के साथ यह किस्सा भी राजीव गांधी तक पहुंचाया कि सती-समर्थक आंदोलनकारियों ने सोनिया गांधी और प्रियंका के बारे में बुरा-भला कहा और जोशी कुछ नहीं कर सके। फिर आयी दुबे और वोरा की बारी, लेकिन उन्हें जोशी की तरह बेआबरू करके निकालने के बजाय केंद्रीय सत्ता में से कुछ हिस्सा देना उचित समझा गया। एक तो उन्होंने जोशी की तरह इस्तीफा देने में हीलहुज्जत नहीं की और दूसरे उन्हें अपने-अपने राज्य में असंतोष भड़काने के लिए छुट्टा छोड़ना ठीक नहीं लगा। मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ल और बिहार में जगन्नाथ मिश्र पलीता लिये पहले से ही घूम रहे हैं। लेकिन दुबे का उत्तराधिकारी खोजना आसान नहीं था। जगन्नाथ मिश्र ज़िस तरह तलवार भांज रहे थे, उसको ध्यान में रखना जरूरी था, फिर बिहार की गद्दी किसी ब्राह्मण को देना जरूरी था, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 'ब्राह्मणों' की गद्दी छिन गयी थी। सीमित विकल्प का लाभ मिला भागवत झा आजाद को। पर दुबे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात राजीव के घोर वफादारों को भी हजम नहीं हो रही है।

दुबे क्यों?: ख़ुद कांग्रेसी यह मानते हैं कि बिहार में दुबे पार्टी के लिए तबाही का पर्याय सिद्ध हुए हैं। बाढ़-राहत कार्यों के साथ जो सलूक किया, वह तो है ही, कानून और व्यवस्था जैसी उनके शासन में कोई चीज थी ही नहीं। बिहार में पिछले एक साल में लगभग दो हजार हत्याएं हुई हैं। अंतर्जातीय युद्धों ने गरीब तबकों को कांग्रेस से बिलकुल काट दिया है। उनकी एक मात्र खासियत है, उनका श्रमिक नेता होना, लेकिन उनको श्रम मंत्रालय की जगह न्याय मंत्रालय दिया गया है। शिवशंकर, जगन्नाथ कौशल और अशोक सेन जैसे प्रमुख वकीलों के बाद बारहवीं पास दुबे को यह मंत्रालय थमा दिया गया है। बकौल आरिफ मोहम्मद अकुशलता के 'राष्ट्रीयकरण' की इससे कोई खराब सबूत नहीं हो सकती। कांग्रेसी सांसदों को अचंभा है कि दुबे को 'डंप' कर देने में पता नहीं क्या दिक्कत थी? जगन्नाथ मिश्र का बिहार में

सांत्वना पुरस्कार: मोतीलाल वोरा (बायें), बिंदेश्वरी दुबे

छाया: अशोक वाही

बिहार फूलों की सेज नहीं: भागवत झा आजाद

छाया: प्रभाकर

हमारे रहते आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेघर नहीं हैं

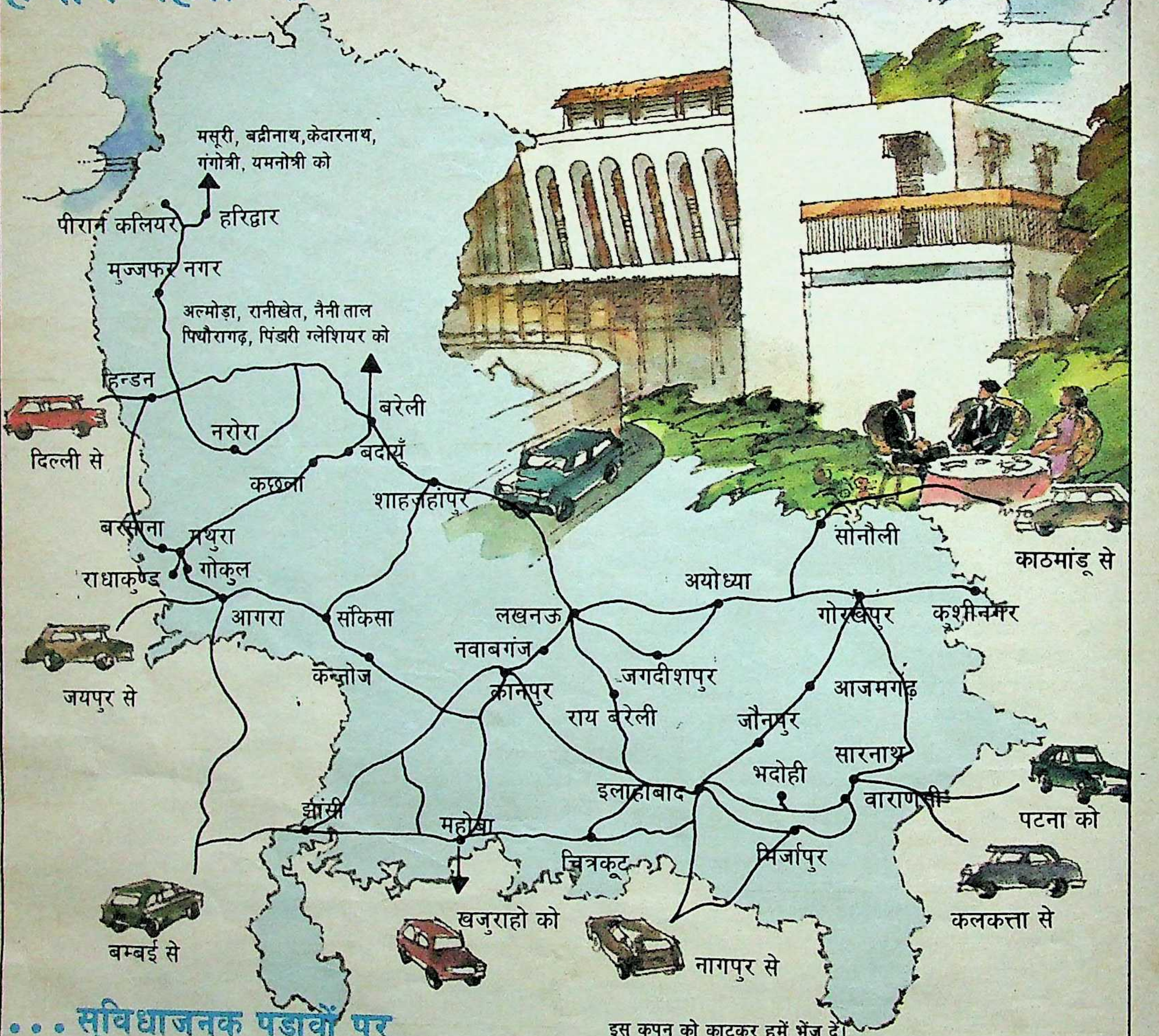
मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री को
पीरान कलियर
हरिद्वार
मुज्जफर नगर
अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनी ताल पिथौरागढ़, पिंडारी ग्लेशियर को
हिन्डन
बरेली
नरोरा
दिल्ली से
बदायूँ
कछला
शाहजहाँपुर
बरसाना
मथुरा
राधाकुण्ड
गोकुल
सोनौली
काठमांडू से
अयोध्या
आगरा
संकिसा
लखनऊ
गोरखपुर
कुशीनगर
नवाबगंज
जयपुर से
कन्नोज
कानपुर
जगदीशपुर
आजमगढ़
राय बरेली
जौनपुर
सारनाथ
भदोही
इलाहाबाद
झाँसी
महोबा
वाराणसी
पटना को
चित्रकूट
मिर्जापुर
खजुराहो को
कलकत्ता से
बम्बई से
नागपुर से

. . . सुविधाजनक पड़ावों पर 35 विश्राम गृहों में आपको अपने घर सा अपनापन मिलेगा।

उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम जिधर भी जाना चाहें यात्रा पर निकल पड़िये। घूमते-टहलते यदि थकान महसूस हो तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के विश्राम गृहों पर पड़ाव डालिए। राह में सुविधाजनक 35 स्थलों पर निर्मित ये विश्राम गृह यात्रा की थकान को मिटाने के लिये बहुत ही आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं। ठहरने, नहाने-धोने, खाने-पीने की पूर्ण व्यवस्था से सुसज्जित उपयोगी विश्रामस्थल जहाँ उत्तर प्रदेश की आतिथ्य परम्परा आपको सुखद एवं निजीपन की अनुभूति देगी।

• आगरा • अयोध्या • इलाहाबाद • कछला • कन्नोज
• कुशीनगर • गोकुल • गोरखपुर • चित्रकूट
• जगदीशपुर • झाँसी • नरोरा • नवाबगंज
• पीरान कलियर • बदायूँ • बरसाना • बरेली • भदोही
• मिर्जापुर • मुजफ्फरनगर • मथुरा • महोबा
• राधाकुण्ड • राय बरेली • लखनऊ • वाराणसी
• शाहजहांपुर • संकिसा • सोनौली • सारनाथ
• हरिद्वार • हिन्डन

उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ आप ठहरना चाहें।

इस कूपन को काटकर हमें भेज दें।

कृपया अपने आवास गृहों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दें

नाम ....

पताः ....

इच्छित भाषाः अंग्रेजी/हिन्दी

उत्तर प्रदेश पर्यटन
चित्रहार भवन 3-नवल किशोर मार्ग,
लखनऊ-226001 उ. प्र.
फोनः 48349, 45252, 47749
• तत्कालिक आरक्षण केन्द्र चन्द्रलोक भवन,
36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 फोनः 322251.

F.N.XIII/-1282

अपना रुतबा है। जब उनको कोई जगह नहीं दी गयी, तो दुबे को लेने की क्या मजबूरी थी?

जाहिर है कि मात्र ब्राह्मणों की नाराजी से बचने के लिए दुबे को सत्ता का हिस्सा दिया गया है। यह राजीव गांधी की राजनीतिक सोच में आये बदलाव का सबूत है। एक समय था, जब वह सत्ता के दलालों, चुके हुए राजनेताओं, जातीय ठेकेदारों के बजाय आधुनिक चाल-ढाल, स्वच्छ और योग्य लोगों को चुना करते थे, लेकिन वह पारंपरिक ढर्रे पर लौट आये हैं और जातपात और तबकों के समीकरण पर उतर आये हैं। यही कारण है कि मुस्लिम तबके में अच्छा असर रखने वाले तारिक और घाघ राजनेता सीताराम के बजाय भागवत झा बाजी मार ले गये। नाम के०के० तिवारी का भी था, लेकिन डर था कि उनकी जबान पर लगाम न होने के कारण वह दूसरी जातियों और दुबे तथा भागवत झा के ब्राह्मण समर्थकों को नाराज कर देंगे। वह दुबे के पीछे काफी समय से पड़े हुए भी थे। आजाद को चुनने में अन्य कारणों ने भी भूमिका निभायी है। एक तो वह वीपी सिंह के निंदाअभियान से सरकार के बचाव करने में सक्षम लगे और दूसरे संसद से उनको अलग करना जरूरी था, क्योंकि कभी-कभी वह संसद में मंत्रियों को असमंजस में डालने वाले सवाल खड़े कर दिया करते थे। फिर पार्टी के महामंत्रीपद से हटा दिये जाने से भी वह नाराज थे। अपेक्षाकृत उनकी छवि भी साफ है।

ब्राह्मण खफा : जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का सवाल है, वाराणसी से श्यामलाल यादव को शामिल करने का औचित्य समझ में नहीं आता। कमलापति त्रिपाठी, बहूजी और लोकपति त्रिपाठी के साथ उनकी बुरी तरह ठनी हुई है। पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने गुमनाम रहते हुए कहा कि यह एक प्रकार से त्रिपाठी-परिवार को करारा तमाचा मारा गया है। इससे ब्राह्मणों के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में पार्टी स्तर पर किये गये परिवर्तन से भी ब्राह्मण खफा हैं। वहां प्रदेश इंका अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के स्थान पर चंदूलाल चंद्राकर (कायस्थ) को लाया गया है। दिग्विजय सिंह को तो जाना ही था। एक तो वह राजपूत हैं और दूसरे अर्जुन सिंह के रिश्तेदार भी, इसलिए पार्टी और सरकार स्तर पर एक जाति के व्यक्तियों को मुखिया नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन अर्जुन सिंह द्वारा सुझाये गये एक ब्राह्मण को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्या दिल्ली को यह डर था कि अर्जुन सिंह के ही व्यक्ति को पार्टी की बागडोर थमा दी, तो मध्य प्रदेश में उनका एकछत्र राज हो जायेगा? लेकिन चंद्राकर के आ जाने से भी अर्जुन सिंह की एकछत्रता पर आंच नहीं आ पायेगी, क्योंकि चंद्राकर उनके मुकाबले में पासंग हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जब अर्जुन सिंह पर राजीव गांधी ने यह भरोसा किया है कि वह अगले चुनावों में पार्टी की नैया किनारे लगाने में सक्षम होंगे, तो फिर उन पर नजर रखने और उन्हें कमजोर करने की आवश्यकता क्या है? अर्जुन सिंह ने अपने पहले के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के आधार को काफी कुछ खतम कर दिया था। उन्होंने जंगल के ठेकेदारों को हटाकर आदिवासियों का दिल भी जीत लिया था। झुग्गी-झोंपड़ियों में रहनेवाले गरीब तबके को वहीं स्थायी आवास की सुविधाएं देकर अपने पक्ष में कर लिया था। ढाई साल पहले उन्होंने अपने अनुयायी हसन सिद्दीकी को भोपाल विधानसभायी सीट पर उपचुनाव भी इसी बलबूते पर जीतने में मदद की थी। इससे पहले शहर पर भाजपा का कब्जा था। अर्जुन सिंह की चुनाव जिताने की क्षमता के कारण ही राजीव गांधी ने वोरा के स्थान पर उन्हें बिठाया है। इसलिए उन पर शक-शुबहा करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

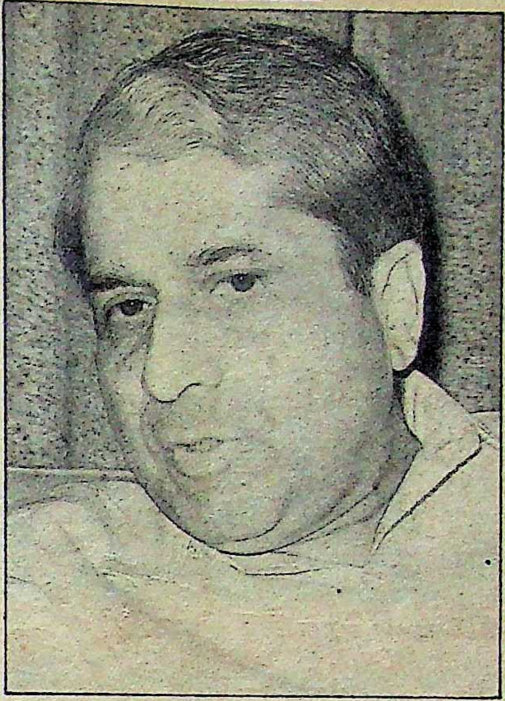

दिन बहुरे : दिनेश सिंह

छाया : फाल एस० गिरोटा

हुक्मउदूली के लिए दंडित : हरिदेव जोशी

यद्यपि ब्राह्मण-मुद्दे को ध्यान में रखकर वोरा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन अफवाह यह भी है कि उनको जल्दी ही हटा दिया जायेगा। बताया जाता है कि उनके पैरवीकार कैप्टेन सतीश शर्मा हैं और यही कारण वोरा को स्वास्थ्य के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय देने का माना जाता है। शर्मा की नागरिक उड्डयन मंत्रालय में रुचि जगजाहिर है और वोरा के आने पर दूर बैठे मंत्रालय चलाने में शर्मा को कोई बाधा नहीं है।

मकसद : दरअसल राजीव गांधी की इस सारी कवायद का एक ही मकसद है—हिंदी क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाना और कमजोर तबकों को तुष्ट करना। लेकिन जिन लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए चुना गया है, उन पर अविश्वास या उन पर लगाम डाले रखने की जो नीति है, उससे यह मकसद पूरा होता नजर नहीं आता। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद उठी गर्द छंटने के बाद कांग्रेसजन यह नहीं समझ पाये हैं कि इससे राजीव गांधी ने क्या खोया और क्या पाया है।

वोरा के पास जैसे स्वास्थ्य के अतिरिक्त नागरिक उड्डयन विभाग है, वैसे पांच अन्य मंत्रियों के पास भी अतिरिक्त विभाग हैं। इनमें वसंत साठे और नारायण दत्त तिवारी भी हैं। तिवारी के खिलाफ काफी समय से ऐसा प्रचार चल रहा था, जिससे उनकी वफादारी संदिग्ध हो सके। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वह वीपी सिंह से काफी करीब हैं और उनसे उनकी लंबी मुलाकात भी हुई है। लेकिन इन विरोधियों को तब बड़ी निराशा हुई, जब तिवारी को राजीव गांधी ने छुआ नहीं। लेकिन राजीव गांधी के दो विश्वस्त व्यक्ति एदुआर्दो फ्लेरियो और अजीत कुमार पांजा को क्रमशः बैंकिंग और आर्थिक मामलों तथा राजस्व का विभाग सौंपा गया है। अजीत पांजा से सूचना मंत्रालय लेने का कारण 'तमस' विरोधी दक्षिणपंथी लाबी का दबाव माना जाता है। जनार्दन पुजारी छह साल से बैंकिंग विभाग काफी उत्साह और ईमानदारी से चला रहे थे, लेकिन अब उन्हें ग्रामीण विकास दे दिया गया है। बताया जाता है कि फ्लेरियो और पांजा को नारायण दत्त तिवारी पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। पुनर्गठन के पहले सुबह के समय अफवाहें गरम थीं कि मई के आसपास तिवारी को उत्तर प्रदेश भेज दिया जायेगा। इस तरह की अफवाहों के बीच राजीव गांधी अपेक्षा रखते हैं कि तिवारी बजट पर ध्यान केंद्रित करें और वफादार बने रहें।

इस फेरबदल से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ब्राह्मण लाबी क्षुब्ध हुई है, जबकि ब्राह्मण कांग्रेस-इ के वोट बैंक हैं। आजाद से मिश्र क्षुब्ध हैं ही। भोपाल में वोरा मंत्रिमंडल के जो तीन मंत्री निकाले गये हैं, वे विद्याचरण शुक्ल के आदमी हैं। उत्तर प्रदेश से श्यामलाल यादव और महाबीर प्रसाद को लेने से त्रिपाठी तथा अन्य ब्राह्मण परेशान हैं। फिर के०के० तिवारी को मंत्री न बनाने से उनके समर्थकों में भी बेचैनी है। वोरा को मंत्रिमंडल में लेने से ब्राह्मणों को कोई खुशी होगी,

राजीव-मंत्रिमंडल के नये चेहरे

यह नहीं माना जा सकता। मध्य प्रदेश में भी उनकी स्थिति कोई मजबूत नहीं है। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा है भी नहीं कि वह अपना प्रभाव क्षेत्र बढा पायें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास स्थायी नहीं है और यह भी कहा जाता है कि मई तक उन्हें और जगदीश टाइटलर को मंत्रिमंडल से हटा दिया जायेगा।

टाइटलर की छुट्टी : टाइटलर से तो वैसे भी राजीव गांधी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। टाइटलर के ऊपर अनेक आरोप हैं—इनमें कुछ गंभीर हैं और कुछ बचकाने। कहा जाता है कि वह बंबई में जुहू हवाई अड्डे को बंद करके किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने की फिराक में थे जो उस जगह व्यापारिक मकसद से गगनचुंबी इमारत बनाना चाहता था। इससे गांधी के सलाहकारों में काफी खलबली थी। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली में टाइटलर ने हवाई अड्डे के पास एक होटल बनाने का ठेका नारंग ग्रुप को दिया है। आपातकाल के दौरान नारंग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे। एक हास्यापस्द आरोप यह है कि प्रधानमंत्री को स्वीडन ले जाने वाले जंबो से टाइटलर ने डैनिश बिस्कुट के दो पैकेट उठा लिये जो कि राजीव गांधी के लिए थे। नागरिक उड्डयन के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि इस तरह के आरोप निरंतर प्रधानमंत्री सचिवालय में पहुंच रहे हैं। राजन जैतली (एअर इंडिया), हर्षवर्धन (वायुदूत) जैसे प्रमुख अधिकारियों की भी अपने मंत्री से ठनी हुई थी। आइटीडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'माया' से कहा, "हमें खुशी है कि उनसे निजात मिल गयी। हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आ रही थी। बहरहाल, नागरिक उड्डयन वोरा को और पर्यटन का अतिरिक्त भार मोहसिना किदवई को सौंप कर राजीव गांधी ने टाइटलर को दोनों महत्वपूर्ण विभागों से वंचित करके उन्हें श्रम मंत्रालय में डाल दिया है।

लेकिन टाइटलर की छुट्टी क्यों नहीं की गयी? १९८० में संजय गांधी के निधन के बाद टाइटलर को बिना धन्यवाद के विदा कर दिया गया था, जबकि उस समय वह एम०एल० फोतेदार जैसी भूमिका निभा रहे थे और सुबह लोगों से मिलने के समय श्रीमती गांधी के वह सहायक हुआ करते थे। लेकिन अब राजीव गांधी के लिए उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है कि दिल्ली के चुनाव राजीव गांधी को मजबूर कर रहे हैं कि वह टाइटलर को अभी बनाये रखें। लेकिन अब अर्जुन सिंह भोपाल चले गये हैं और हरकिशन लाल भगत दिल्ली के अभियान के संचालक होंगे। विभागों के बटवारे के बाद भगत कैबिनेट में तीसरे नंबर पर आ गये हैं। वास्तव में राजीव गांधी द्वारा उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपना इस बात का संकेत है कि टाइटलर के मतदाताओं को उन्होंने भगत की झोली में डाल दिया है।

रंगनाथ मिश्र कमीशन ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी है कि दिल्ली के सिख उन्हें शक की नजर से देखते हैं। इसके बावजूद उनके साथ राजीव गांधी ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि बजट सत्र में टाइटलर के खिलाफ प्रश्न जरूर उठाये जाते। टाइटलर पर आरोप है कि नागरिक उड्डयन और एयरलाइंस में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की भरमार है।

हिंदी-क्षेत्र की रक्षा : इस तरह राजीव गांधी की प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। उन्होंने ये परिवर्तन आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखकर और कमजोर तबकों को संतुष्ट करने के लिए किये हैं। अब ये कितने प्रभावी सिद्ध होंगे, भविष्य ही बतायेगा। उन्होंने प्रमुख रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा (उत्तर प्रदेश से १३ और बिहार से ६) मंत्री हैं। इन दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और बिहार) से १३९ लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। इन्हीं दो प्रदेशों में वीपी सिंह ने बार-बार दौरे किये हैं और राजपूत वोटों पर उनका हिस्सा साफ नजर आता है। यही कारण है कि १७ सालों बाद कांग्रेस के बुरे दिनों में अन्य दलों में शामिल हो जाने वाले दिनेश सिंह को मंत्री बनाया गया है। उन्हें वीपी सिंह की 'काट' के रूप में लाया गया है। उन्होंने लोकसभा

पेंशन के रूप में राज्यपाल-पद : राम दुलारी सिन्हा

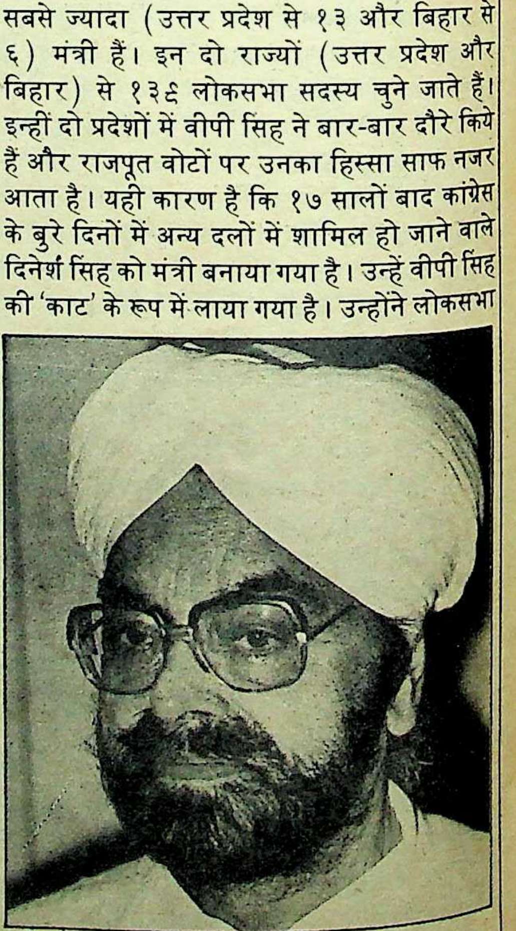

मंत्रिमंडल से छुट्टी : जी०एस० ढिल्लों

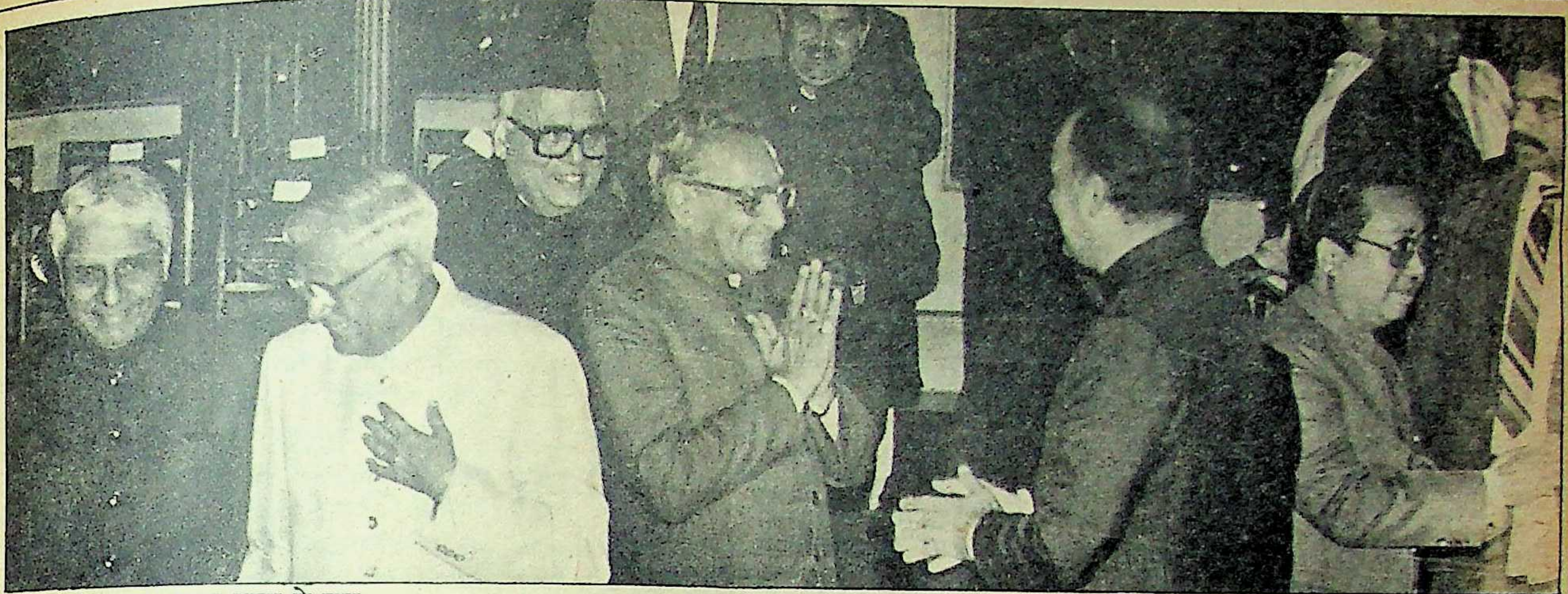

कृतज्ञता प्रकाशन : शपथ ग्रहण के बाद

में वीपी सिंह पर काफी जुबानी हमले किये थे। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के ऊंची जाति के राजपूतों में उनका खासा दबदबा है और यही उनके पक्ष में गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन सभी प्रमुख राजपूत परिवारों से उनके संबंध हैं, जिनसे वीपी सिंह के संबंध हैं, लेकिन उन्हें जल संसाधन का महत्वहीन विभाग दिया गया है। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वह विदेश अथवा वाणिज्य मंत्री थे। वास्तव में नटवर सिंह के बाद विदेश मंत्रालय का काम खुद राजीव गांधी देख रहे हैं और वाणिज्य मंत्रालय नारायण दत्त तिवारी के पास बना हुआ है। दिनेश सिंह को महत्वहीन विभाग का दिया जाना प्रदर्शित करता है कि विभागों के बंटवारे के समय राजीव गांधी का ध्यान चुनाव की तरफ था न कि प्रशासन में सुधार की तरफ। दिनेश सिंह को नागरिक उड्डयन और पर्यटन, सूचना एवं प्रसारण और वाणिज्य मंत्रालयों में से एक दिया जा सकता था। लेकिन ये सभी विभाग दोहरी जिम्मेदारी के रूप में दे दिये गये हैं जिससे प्रशासन को सहायता मिलने की कोई संभावना ही नहीं है।

बदलती नीति : दरअसल, चुनाव की चिंता ने उन्हें तमाम मूल्यों, विचारधाराओं और राजनीति में नये चेहरों को मौका देने के अपने वायदों को भूल जाने को मजबूर कर दिया। ईमानदार व्यक्तियों और साफ-सुथरी सरकार की उनकी अवधारणा भी अब आडंबर दिखायी देने लगी है। जातीय समीकरण और वोट प्राप्त करने की योग्यता वाले व्यक्ति ही अब उनकी नीति के अंग हैं। अब वह श्रीमती गांधी के समय में लौट आये हैं। जब एस०के० पाटिल, एल०एन० मिश्रा और रजनी पटेल अपने फंड इकट्ठा करने और संगठन खड़ा करने की योग्यता के कारण श्रीमती गांधी के प्रिय थे, जबकि गुंडूराव और प्रणब मुखर्जी का कोई आधार नहीं था, इसलिए उनके आज्ञाकारी होने को बाध्य थे।

सी०के० जफर शरीफ, जिन्हें १९८४ में लोकसभा सीट के लिए टिकट तक नहीं दिया गया था, उन्हें केवल इसलिए नहीं लिया गया कि वह मुस्लिम हैं, बल्कि इसलिए लिया गया है कि वह विपक्ष के 'काट' के लिए काम आ सकते हैं। उन्हें कर्नाटक में पार्टी की सहायता के लिए और उत्तर भारत में मुसलमान वोट हथियाने के लिए याद किया गया है। रेलवे राज्यमंत्री के रूप में उन्होंने रेलमंत्री अब्दुल गनी खान चौधरी का जीना हराम कर दिया था। शरीफ एक समय राजीव की नीतियों की जमकर आलोचना करते थे, मगर अब वह चुप हैं। सुमति उरांव को बिहार के पृथकतावादी झारखंड आंदोलन को बेअसर करने के लिए लिया गया है। वह कार्तिक उरांव की पत्नी हैं जिनकी आदिवासियों पर पकड़ जगजाहिर है। पिछले संसद सत्र में वह आदिवासियों के खिलाफ हो रही ज्यादती के लिए केंद्रीय नेतृत्व से लिखित लड़ाई लड़ती रही हैं। पी० नामग्याल को लद्दाख क्षेत्र में नेशनल कांफ्रेंस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शामिल किया गया है। बिहार के बुजुर्ग और एक समय के वरिष्ठ मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही को तीन वर्ष के इंतजार के बाद मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। वह भूमिहारों के नेता हैं। बहुत दिनों बाद हाईकमान ने यह महसूस किया है कि कृष्णा शाही के मुकाबले वह ज्यादा प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। कृष्णा शाही को राजीव गांधी ने अपने उस समय के मापदंड—विनम्र, आधुनिक और युवा—के आधार पर चुना था, लेकिन अब यह सब खतम हो गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो पूर्व अध्यक्ष डूमर लाल बैठा और रफीक आलम को उपमंत्री बनाया गया है। बैठा और रफीक को उपमंत्री बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का अवमूल्यन करने से राजीव गांधी जरा भी नहीं हिचकिचायें। अगले चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजीव गांधी द्वारा हर नियम का ताक पर रख देने का यह एक और उदाहरण है।

बहरहाल, राजीव गांधी के पार्टी अध्यक्ष बने रहने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि तीन साल बाद राजीव

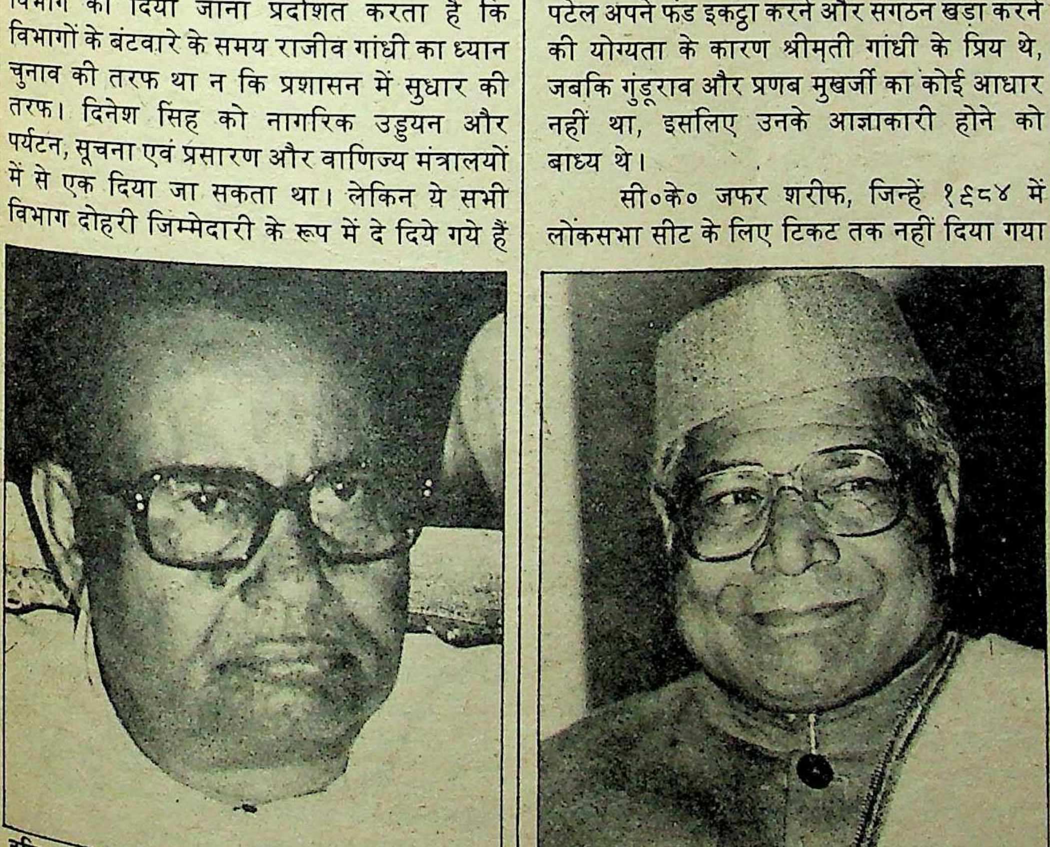

हरिजन कोटा : डूमरलाल बैठा (बायें) और महावीर प्रसाद

प्रेमशंकर झा का नजरिया

मंत्रिमंडल में फेरबदल

एक निरर्थक कवायद

प्रेमशंकर झा: 'हिंदुस्तान टाइम्स' के पूर्व संपादक, देश के विख्यात अर्थ विशेषज्ञ व राजनीतिक समीक्षक

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रविवार १४ फरवरी को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो घोषणा की, उससे उनकी मंशा के बारे में किसी को संदेह नहीं है। मंत्रिमंडल के १३ नये चेहरों में से ८ बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। यह केवल संयोग नहीं कहलायेगा कि ऐन यही दोनों राज्य हैं, जहां कांग्रेस को विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीछे गोलबंद ताकतों की सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

श्री गांधी की नजर अगले आम चुनावों पर है, किंतु उनके अन्य उद्देश्य भी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वमुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और बिहार के बिंदेश्वरी दुबे को केन्द्रीय कैबिनेट में लिये जाने का फैसला इस दिली ख्वाहिश को उजागर करता है कि नये मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की बिहार में और अर्जुन सिंह की मध्य प्रदेश में राज्य विधायक दलों पर जल्द से जल्द मजबूत पकड़ हो।

गत डेढ़ दशक के अनुभवों ने सिद्ध किया है कि पार्टी आलाकमान द्वारा राज्य कांग्रेस पार्टियों पर थोपे गये मुख्यमंत्रियों को उन लोगों के साथ अधिकार पूर्वक कार्य करने में दिक्कतें आती हैं जो उनके पूर्व उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्वमुख्यमंत्री को अपने व्यापक प्रभाव के कारण पार्टी के अंदर अपने कट्टर समर्थकों की टोली बनाने में सहायता मिलती है। नतीजतन, वह नवागंतुक मुख्यमंत्री की योजना में पलीता लगाने में अहम भूमिका निभाता है।

यह सही है कि अर्जुन सिंह का मध्य प्रदेश में तीन साल की गैरमौजूदगी के बावजूद, दबदबा कायम है और उन्हें श्री आजाद की तुलना में कम समस्याओं से जूझना होगा, किंतु उनको भी अपना पथ श्री वोरा के हट जाने से निष्कंटक और सहज लगेगा। श्री गांधी द्वारा बिहार व उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को अपने मंत्रिमंडल में लिये जाने से भी इस धारणा को बल मिलता है कि उनका मुख्य लक्ष्य है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रास्ता हमवार करना।

इस प्रकार यह कैबिनेट फेरबदल राजीव गांधी के एक राजनीतिज्ञ के रूप में उभरकर सामने आने का द्योतक है। ३७ माह पूर्व जब वह सत्ता में आये थे, तब राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने उनकी राजनीतिक क्षमताओं में संदेह प्रगट करते हुए, उन्हें टेक्नोक्रैट (तकनीशियन) अथवा प्रतिगामी पायलट करार दिया था और उन्होंने राजीव गांधी की इस बात के लिए आलोचना की थी कि उन्होंने अपने यार-दोस्तों को पहले तो संसदीय सचिव और बाद में मंत्री का दर्जा दिया। कांग्रेस-इ में राजीव गांधी की घटती साख के लिए भी उनके यार दोस्तों को दोषी ठहराया गया। इन्हीं मित्रों की अधकचरी सलाह पर जल्दबाजी में उन्होंने असम तथा पंजाब में असंतुष्टों के साथ समझौते किये और कई अन्य हानिकारक कदम उठाये।

गत वर्ष की घटनाएं बताती हैं कि श्री गांधी ने अपने तथा अपने मित्रों के बारे में इन मूल्यांकनों को स्वीकार कर लिया है। आज उनके घनिष्ठतम पूर्व-सहयोगी वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू और अरुण सिंह राजनीति के अंधेरे में हैं और श्रीमती गांधी के दिनों में हर तरह के दांवपेंचों में माहिर शिवशंकर, मूपनार, बूटा सिंह, फोतेदार, एच०के०एल० भगत और यहां तक कि प्रणब मुखर्जी भी अब पूर्णतया उनके पक्ष में हैं।

श्रीमती गांधी के समय में कांग्रेस-इ की एक मात्र खासियत यह थी कि इसके वरिष्ठ नेताओं ने आम जनता को अहमियत देनी बंद कर दी थी। वे मानते थे कि मतदाताओं को राजनीतिक समझ नहीं है और उन्हें नारों तथा ऐसे कार्यक्रमों से भरमाया जा सकता है जो उनमें यह मुगालता पैदा कर सके कि कांग्रेस-इ वास्तव में छोटे तबके के लोगों का ध्यान रखती है और अमीरों एवं ताकतवर लोगों के खिलाफ उनकी जंग में वह आम आदमी के साथ है। अतः इन कांग्रेसी नेताओं की यह धारणा बन गयी थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय प्रमुख लोगों को रियायतें और धन आदि का प्रलोभन देकर एक चुनाव-विजेता पार्टी का गठन किया जा सकता है।

बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना यह संकेत देता है कि श्री गांधी ने श्रीमती गांधी के समय के कांग्रेसी नेताओं की उक्त धारणा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन श्रीमती गांधी और राजीव गांधी के तौर-तरीकों में काफी अंतर है। अपने ही द्वारा नामजद प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाकर राजीव गांधी ने श्रीमती गांधी का ही नहीं, बल्कि अपने नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू के तौर-तरीकों का अनुसरण किया है। नाकारा हो रहे कांग्रेस-इ संगठन में आम सहमति पैदा करने और पार्टी-नेताओं में व्याप्त विवादों को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने पुराने अस्त्र का प्रयोग किया है और इसका लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस-इ संगठन की गिरती साख को फिर से उठाने के उपाय में काफी देर हो चुकी है।

मतदाता अब अराजनीतिक नहीं रह गया है। वह अब ऐसी मिट्टी भी नहीं है, जिसे स्थानीय जातीय वर्चस्व, सामंती शोषण और भूपतियों के प्रभुत्व से मनचाहा रूप दिया जा सके। नया मतदाता वंशानुगत लोकतंत्र का नहीं, शिरकतशुदा लोकतंत्र का हिमायती है। वह चाहता है कि उसके नेता मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हों; न कि दिल्ली के प्रति। उसके लिए वह भ्रष्टाचार भी असहनीय होता जा रहा है जो ब्लाक स्तर से लेकर लोकसभा की राजनीतिक प्रणाली को संचालित कर रहा है। आज मतदाताओं के दिमाग में कांग्रेस की छवि वंशवाद और भ्रष्टाचार से युक्त ऐसी पार्टी की छवि है, जिसमें श्री गांधी मात्र शिखर पर आसीन लोगों को बदलकर निखार नहीं ला सकते। आगामी आम चुनावों में अभी २२ महीने शेष हैं, लेकिन वस्तुतः इसमें भी संदेह है कि नीतियों में भारी बदलाव लाकर भी इस अवधि में कांग्रेस-इ की साख को उठाया जा सकता है। श्री गांधी इसमें कामयाब हो सकते थे, यदि वह अपने ही द्वारा उठाये गये १९८५ के सुधारवादी कदमों का अनुसरण करने के लिए कांग्रेस-इ संगठन को बाध्य कर देते। लेकिन वी०पी० सिंह को पहले मंत्रिमंडल और बाद में पार्टी से निष्कासित करने के साथ ही उन सारे सुधारवादी कार्यक्रमों पर पानी फिर गया और अब यह कहना मुश्किल है कि मंत्रिमंडल के इस फेरबदल की कवायद का श्री गांधी को कोई खास लाभ मिल सकेगा। अतः कांग्रेस-इ का आगामी आम चुनावों में भविष्य एक बार फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवस्था को लगनेवाले अप्रत्याशित झटकों से लाभ उठाने की उसमें कितनी क्षमता है? ■

गांधी ने पार्टी में अपनी स्थिति और इस वास्तविकता को पहचान लिया है कि भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के बाद वह सत्ता के दलालों और विचौलियों से लड़ने की स्थिति में अब नहीं हैं। निष्ठा भी अब जा चुकी है। कई खतरे उठाये गये हैं, यद्यपि १९८९ की बाधा पार करने के लिए अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी और भागवत झा आजाद जैसे लोगों को लगा दिया गया है।

अब वे दिन काफूर हुए: पुरानी सभी बातें चली गयी हैं। वरिष्ठ नेताओं की छंटनी करके साफ-सुथरी और युवाओं द्वारा चलायी जाने वाली सक्षम सरकार के लिए तब राजीव ने समर्पित और गैरपरंपरा वाले लोगों को मंत्रिमंडल में लिया था। अब उनमें से ज्यादातर बाहर कर दिये गये हैं। अरुण सिंह को फिर से शामिल नही किया गया है। किसी राजा, राजकुवर और पब्लिक स्कूल के उनके मित्र को भी नहीं लिया गया हैं। ज्यादातर राजनीतिज्ञों को वोट हासिल करने या विपक्ष को कमजोर करने के लिए लिया गया है। विभागों के बंटवारे में भी किसी की योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है।

मीडिया और पार्टी सदस्यों के अनुसार माधवराव सिंधिया का नाम पत्ता कटने वाले मंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर था, मगर वह बच गये हैं। वास्तव में कड़ी मेहनत करने वाले कुछ मंत्रियों में से सिंधिया हैं और उनको कैबिनेट में लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो उनकी पुत्री की शाही शादी और दूसरी कैबिनेट मंत्री बन जाने के बाद अर्जुन सिंह से लड़ने के लिए उनकी स्थिति का और मजबूत होना। मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी समय से दोनों आमने-सामने हैं। तीन साल पहले राजीव गांधी इन सब चीजों की परवाह नहीं करते थे। फेरबदल के बाद इस क्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ की परेशानियां साफ हो गयी हैं।

दुर्भाग्यवश इस फेरबदल के द्वारा राजीव गांधी एक सुप्रीमो और ईमानदार राजनीतिज्ञ वाली विश्वसनीयता दुबारा नहीं पा सकेंगे, जो कि अपनी राजनीति की शुरुआत में उन्होंने दिखलायी थी। वह उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ करने में असफल रहे हैं। गलत नीतियों के लिए काफी विरोध होने के बावजूद जे०बी० पटनायक अपनी गद्दी पर जमे हुए हैं, क्योंकि राजीव गांधी बीजू पटनायक की टक्कर का कोई दूसरा नेता ढूंढ़ने में असफल रहे हैं। बीजू पटनायक में उनकी कांग्रेस को हराने का दमखम है। अतः फिलहाल उन्होंने यह समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। वीर बहादुर का मामला और भी जटिल है। उन्होंने हाईकमान को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया है कि अब और विधायक वीपी सिंह के पाले में नहीं जायेंगे। लेकिन इस समय सारा जोड़-तोड़ चुनाव को लेकर है। वीर बहादुर इस समय मुश्किलों में घिरे हैं। वह बहुत अच्छे चुनाव प्रबंधक हैं, मगर किसान इस समय आंदोलन पर उतारू हैं और जनता भी उनके साथ है। ऐसी स्थिति में वीर बहादुर पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन राजीव ने फिलहाल दिनेश सिंह का ठाकुरों में और महाबीर प्रसाद का पिछड़े वर्गों में प्रभाव देखने का फैसला किया है। वह मुलायम सिंह और बहुगुणा में जनमोर्चा को लेकर पड़ी दरार का आकलन भी कर रहे हैं। मई तक वीर बहादुर को खतरा नहीं है, अलबत्ता किसान आंदोलन ज्यादा जोर न पकड़े। वीर बहादुर के विदा न होने की एक और वजह है, किसी विवादयुक्त विकल्प का न होना। यदि नारायण दत्त तिवारी लौटने को राजी न हों, तो लोकपति मजबूत दावेदार हैं, मगर लोकपति के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाना त्रिपाठी परिवार का राजनीति से सफाया ही होगा। और राजीव गांधी ऐसा फिलहाल नहीं कर सकते। ठीक ऐसी ही मुश्किल महाराष्ट्र में है, जहां वसंत दादा पाटील और शरद पवार दोनों हाईकमान के वफादार नहीं हैं। राजीव गांधी चौहान की बनिस्बत उनसे ज्यादा डर रहे हैं। यही कारण है कि गुजरात, महाराष्ट्र यहां तक कि राजस्थान से किसी को नहीं लिया गया है। यदि राजस्थान में राजा मानसिंह की हत्या वाले मामले को लेकर आंदोलन जोर पकड़ता है और हरिदेव जोशी साथ छोड़ देते हैं, तो केवल १२ विधायकों के बहुमत वाली कांग्रेस को जयपुर में मुश्किल हो सकती है।

फिर से ताजपोशी: शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए

ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण राजीव निकट भविष्य में चुनाव नहीं करायेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल से ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि जल्दी ही वह चुनाव कराने में दिलचस्पी रखते हैं। शंकरानंद बोफोर्स कमेटी की रपट, राज्यसभा के चुनाव, बजट सत्र की समाप्ति के बाद किसी फेरबदल से चुनाव के समय के बारे में कोई संकेत मिलेंगे।

इस सबके पहले अपनी आजमाइश वह इलाहाबाद सीट सहित दो उपचुनाव में करेंगे। इनके परिणामों से ही पता चलेगा कि लोगों का विश्वास उन पर कितना लौटा है और जिन लोगों का चुनाव उन्होंने किया है, उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिलती है, तो वह चुनाव की भूमिका के रूप में जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास सीमित समय और सीमित लोग हैं। अर्जुन सिंह, हरकिशन लाल भगत, भागवत झा आजाद या दिनेश सिंह पर भविष्य का कार्यभार होगा, जबकि राजीव अपनी छवि को लेकर भी चिंतित हैं। जिनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, उनके झगड़े और निश्चित रूप से गिरती आर्थिक स्थिति जो कि इस साल के अंत तक लगभग ३५००० करोड़ के घाटे तक पहुंच जायेगी, उनकी चिंता का विषय होगा।

फेरबदल से उपजी नाराजगी: फेरबदल से डी०पी० यादव, आर०एल० भाटिया, कल्पनाथ राय और के०के० तिवारी खास तौर पर नाराज हैं। कहा जाता है कि राय ने के०पी० उन्नीकृष्णन से कहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कहा जाता है कि आर०एल० भाटिया को यादव के साथ अंतिम समय में बूटा सिंह के कहने पर नहीं लिया गया। बहुत से ऐसे नेताओं के पास, जिन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, नये मंत्रियों के बारे में उक्त प्रकार की कई कहानियां हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ दुखी सांसदों और विधायकों ने अरुण नेहरू के घर पर मुलाकात की है। इसलिए राजीव गांधी ने मंत्रिमंडल में और परिवर्तनों की बात कही है।

कांग्रेसियों को प्रलोभनों की जरूरत है। जिस छड़ी से युवा राजीव ने उन्हें हांका है और जिससे उन्हें नियंत्रण स्थापित करने में सफलता मिली है, वह उनके मित्रों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नहीं दूर कर पायेगी। रिपोर्टें और सफायी राजनीतिक परिदृश्य को साफ नहीं करती हैं। वह चुनाव कराने का निर्णय तब तक नहीं लेंगे जब तक कि अवधि पूरी न हो जाये या फिर उनकी छवि साफ न हो जाये। अपने रक्षकों में परिवर्तन करना फर्श से धूल झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार में सत्ताहस्तांतरण करवाया है, वह नायाब है।

यों तो मध्यप्रदेश में अर्जुनसिंह के अनुयायी और समर्थक उनकी वापसी का तूमार काफी दिनों से बांध रहे थे, किंतु उनकी योग्याता, उनके परामर्शदात्री महत्व और मध्य प्रदेश की राजनीति के पारंपरिक शांत चरित्र को देखते हुए यह संदिग्ध था कि आलाकमान उन्हें मोतीलाल वोरा के स्थान पर देश के सबसे बड़े प्रांत की बागडोर पुनः सौंपेगा। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कयास यह था कि अर्जुनसिंह की पसंद के किसी युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाया जायेगा। मगर ये सारे कयास धरे-के-धरे रह गये और आलाकमान ने ऐन बजट सत्र के दौरान जैसे-तैसे गाड़ी खींच रहे मोती लाल वोरा की 'छुट्टी' कर एक तो रातो-रात सारे राजनीतिक समीकरण बदल दिये, दूसरे, यह भी स्पष्ट कर दिया कि सत्ता के मुखिया की ढिलाई, राजनीतिक अदूरदर्शिता और दुर्बलता को अधिक दिनों तक सहन करना न तो संभव है और न ही सत्तारूढ़ दल के हित में।

वोरा को हटाने में यदि आलाकमान ने थोड़ी बहुत प्रारंभिक हिचकिचाहट नहीं दिखाई होती और कतिपय बड़े नेताओं ने रोड़ा नहीं अटकाया होता, तो तय था कि वोरा पांच फरवरी को प्रारंभ राज्य विधान सभा के सत्र के पूर्व विदा हो गये होते, लेकिन दिल्ली के कतिपय बड़े और प्रभावी नेताओं को वोरा की योग्यता के बजाय उनकी सदाशयता और सीधेपन ने मोह रखा था, लिहाजा, दिल्ली दरबार के फैसले और उसके अमल में दस दिनों का फासला या व्यवधान उत्पन्न हो गया।

संकेत: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद से मोतीलाल वोरा की विदाई और आलाकमान के बनते-बिगड़ते मूड का पहला संकेत तब मिला था, जब छिंदवाड़ा से निर्वाचित इंका सांसद कमलनाथ ने वोरा को 'अक्षम' करार देकर उन पर करारे प्रहार किये थे। दिल्ली में जब प्रतापभानु शर्मा, रामेश्वर नीखरा, बालकवि बैरागी, के०एन० प्रधान आदि सांसदों ने वोरा का पक्ष लिया था, तो कमलनाथ ने अपने स्वभाव व प्रकृति के विपरीत दिल्ली में बयान जारी कर वोरा और उनकी सरकार के बारे में अपनी धारणा को फिर दोहराया था। (देखिये 'माया' का—अंक) कमलनाथ के तेवर और बयान से यह बात उद्घाटित हो गयी थी कि हाईकमान वोरा को हटाने का मूड बना रहा है। दिल्ली दरबार के मिजाज से वाकिफ कमलनाथ का वक्तव्य वोरा और उनके हिमायतियों व आकाओं के लिये चेतावनी थी, मगर वोरा अपने ढंग और ढर्रे को सुधार नहीं सके।

सूत्रों के अनुसार आलाकमान जहां वोरा की झगड़ा-टंटा और बखेड़ा खड़ा न करने की प्रवृत्ति से प्रभावित था, वहीं उनके कमजोर प्रशासन और अदूरदर्शिता से क्षुब्ध भी। हाईकमान ने अपने हिसाब से वोरा को कुछ कर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया, मगर जब इस लीज-दर-लीज का कोई माकूल नतीजा नहीं निकला, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा कि वोरा की 'छुट्टी' की जाये। यह एक अजीब संयोग है कि वोरा ने तेरह तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तेरह को ही उन्हें यह कुरसी छोड़नी पड़ी। तेरह के चमत्कार के शिकार वोरा अगर एक माह और टिके रहते तो १३ मार्च को अपने मुख्यमंत्रित्व-काल के तीन वर्ष पूरे कर लेते। प्रधानमंत्री के एक नजदीकी सांसद ने 'माया' को बताया कि प्रधानमंत्री ने करीब एक पखवाड़ा पहले वोरा को चलता करने का मन बना लिया था। २७ जनवरी को जब वह गुवाहाटी गये, तो अर्जुनसिंह को भी साथ लेते गये। रास्ते में विमान में ही प्रधानमंत्री ने उन्हें यह संकेत दे दिया कि वह उन्हें वापस मध्यप्रदेश भेजना चाहते हैं। हर हाल में निर्विकार रहने के अभ्यस्त अर्जुनसिंह ने इसे चुपचाप सुना। नेता के आदेश को शिरोधार्य न करना, चूं-चपड़ या टीका-टिप्पणी करना अर्जुनसिंह के स्वभाव में नहीं है। एक अन्य प्रभावशाली सांसद के अनुसार एक फरवरी को यह बात वोरा तक भी पहुंच गयी थी, परंतु प्रतीत होता है कि वोरा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने स्वभाव के विपरीत कुछ उलटे कदम उठा लिये। माणक अग्रवाल, मनोहर बैरागी, कुमारी माबेल रिबेलो और शंकरलाल ताम्रकार के क्रम में उन्होंने अपने दो नजदीकी लोगों राजेंद्र भटनागर और किशन पंत को सरकारी निगमों का अध्यक्ष और अनेक को संचालक-मंडल का सदस्य बना दिया। इन नियुक्तियों पर अर्जुनसिंह के अनुयाइयों के इस आशय के प्रचार-घोष में काफी टीका-टिप्पणी हुई कि वोराजी जा रहे हैं। समर्थकों को अर्जुनसिंह की वापसी की भनक लगने का आभास इससे होता है कि एक तो अर्जुनसिंह का इन दिनों प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर इस अंदाज में भावभीना और जोरदार स्वागत हुआ, मानो कोई लाड़ला बरसों बाद लौटा हो, दूसरे अर्जुनसिंह समर्थक एक अंग्रेजी समाचारपत्र ने जोरशोर से वोरा के जाने की घोषणा कर डाली। दो फरवरी से पांच फरवरी के बीच वोरा की विदाई की हवा सत्ता के गलियारों में जोर मारती रही। पांच फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होने पर एक बारगी लगा कि वोरा की विदाई सत्रसमाप्ति तक के लिए टल गयी है। ऐसी स्थिति में भी उक्त दैनिक अपनी इस पूर्वोक्ति पर टिका हुआ था कि वोरा की छुट्टी होने जा रही है। 'माया' के सूत्रों के अनुसार इसमें विलंब इसलिये हुआ, क्योंकि दिल्ली में उप राष्ट्रपति डा० शंकरदयाल शर्मा ने वोरा को हटाने की खबर लगने पर इसका विरोध किया, जिससे प्रधानमंत्री संकोच और दुविधा में फस गये।

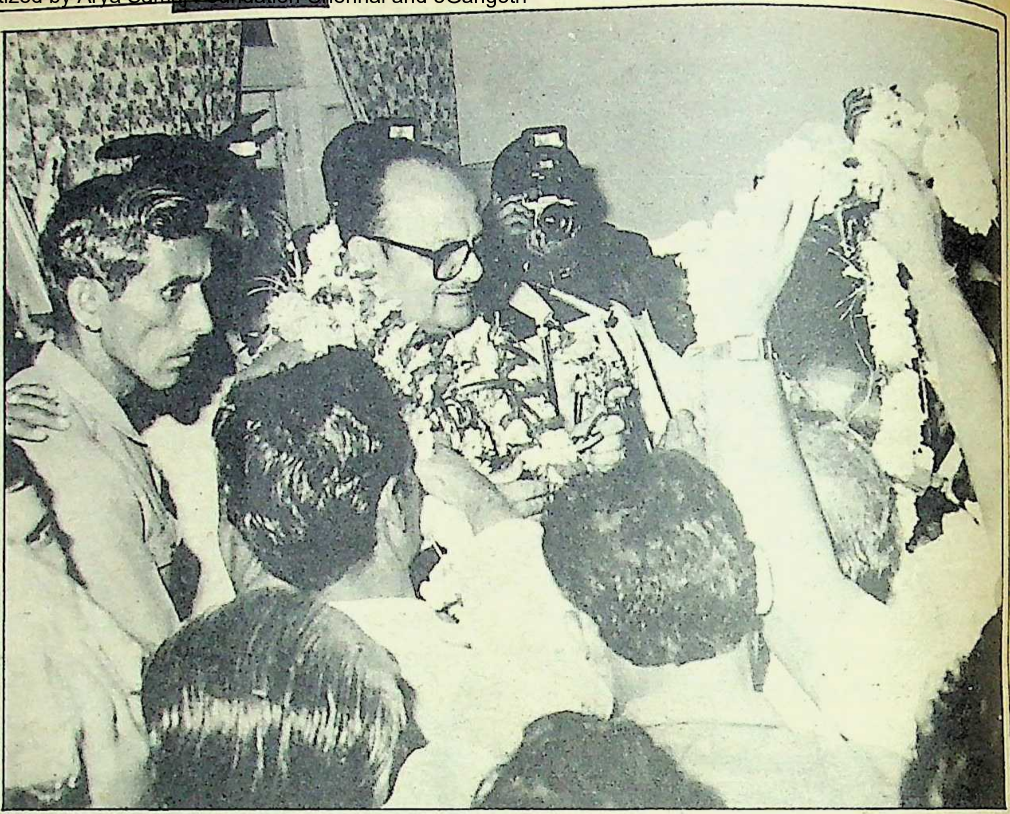
खुशी मनायें या गम ? : अर्जुन सिंह

घटनाक्रम में तेजी: १२ और १३ फरवरी को अकस्मात घटना चक्र बड़ी तेजी से घूमे और घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि सारे रथी; महारथी अवाक रह गये। १२ फरवरी को वोरा को दिल्ली तलब किया गया। वोरा अपने निजी स्टाफ और सूचना-आयुक्त ललित कुमार जोशी के साथ करीब शाम साढ़े सात बजे दिल्ली पहुंचे। प्रयोजन पूछने पर उन्होंने जिज्ञासुओं को आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर टाल दिया। दिल्ली दरबार में बड़े जतन से बनाया हुआ वोरा का रक्षा-कवच ऐन मौके पर काम न आया। उनके समर्थक सांसद या तो मुगालते में रहे या गाफिल। प्रभारी महामंत्री रामरतन राम के सारे मंत्र बेकार गये। करीब चार घंटों के प्रवास में वोरा की अति-विशिष्ट लोगों में से केवल केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बूटा सिंह से भेंट हुई और वह रात करीब डेढ़ बजे भोपाल लौट आये। अगले दिन १३ फरवरी को वोरा मुरारी बापू का प्रवचन सुनने उज्जैन चले गये। वहां उन्होंने अत्यंत

केवल मध्य प्रदेश संभालिए : अर्जुन सिंह को गुलदस्ता देते हुए राज्यपाल प्रो० के०एम० चांडी

तल्लीनतापूर्वक एक घंटे मे अधिक समय तक मुरारी बापू का प्रवचन मुना। अपराह्ण दिल्ली से फोन कर बूटासिंह ने उनमे त्यागपत्र देने को कहा। वोरा के समक्ष अब इनकार या विलंब के लिए कोई मौका नहीं था, अत: उन्होंने मांय पांच बजे करीब दो वर्ष ११ माह पूर्व मंभाले अपने पद मे इस्तीफा दे दिया।

वोरा ने अपने इस्तीफे की सूचना सबसे पहले मंत्रियों की बैठक में दी। पांच मंत्रियों—बी०आर० यादव, महेश जोशी, चित्रकांत जायसवाल, गंगा पोटाई और हरिहर प्रसाद शर्मा तथा संसदीय सचिव कुमारी फिरोजा अली को जब उन्होंने त्यागपत्र की सूचना दी, तो मभी हैरत में पड गये। संयोग से उस समय रामकिशोर शुक्ल लखनऊ, भारत सिंह, डा० कन्हैयालाल शर्मा और बंशीलाल धृतलहरे बिलासपुर, शिवभानु सोलंकी इंदौर और विट्ठल भाई पटेल गुना मे थे। एक अन्य मंत्री बालेंदु शुक्ल अपने भांजे की शादी में भाग लेने गये थे और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल भी बिलासपुर में थे। परिवर्तन की खबर पाकर ये सभी नेता और अलग स्थानों से विधायक गण भोपाल के लिए चल पड़े। अर्जुन-शिविर में इस घटना को प्रतीक्षित विजय के रूप में आंका गया और वहां जश्न शुरू हो गया। इसके विपरीत वोरा समर्थक सकते में आ गये। वोरा और अर्जुनसिंह के बीच चले लंबे शीतयुद्ध के बाद वोरा समर्थकों को वोरा के जाने से अधिक तकलीफ कुंवर साहब की वापसी से थी। बाद में केंद्र सरकार में वोरा के शरीक होने की सूचना ने इन लोगों के घावों पर मरहम और दर्द-निवारक दवा का-सा काम किया। वोरा के इस्तीफे के बाद अधिकृत तौर पर यह सूचना सप्रेषित की गयी कि अगले दिन पांच बजे शाम को नये नेता के चुनाव के लिए इंका विधायक दल की बैठक होगी। किंतु रात में लगभग दस बजे 'माया' के दिल्ली सूत्रों ने खबर दी कि अर्जुनसिंह फिर से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और वह कमलनाथ, हरिकिशन लाल भगत, सीताराम केसरी और रामानंद लाल यादव के साथ विमान से भोपाल के लिए रवाना हो गये हैं। श्री सिंह रात्रि १२ बजकर, २० मिनट पर राजकीय विमान से भोपाल पहुंचे, तो उनके साथ उपरोक्त नेताओं के अतिरिक्त उनकी पत्नी श्रीमती सरोज सिंह और समधी प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह भी थे। उस समय तक अधिकांश विधायक भोपाल से बाहर थे, किंतु सर्द रात के बावजूद भी सिंह समर्थक नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इस बीच आलाकमान का १४ फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला बदल चुका था। अर्धरात्रि में ही जितने विधायक मौजूद थे और आसपास से जितने आ सके, उनकी मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक का आयोजन आलाकमान के फैसले पर औपचारिक मोहर लगाने के मकसद से किया गया था और यह काम आननफानन हुआ। मोतीलाल वोरा के प्रस्ताव और चित्रकांत जायसवाल के अनुमोदन के बाद मध्यरात्रि में डेढ़ बजे इंका के खजांची सीताराम केसरी नें अर्जुनसिंह के सर्वसम्मत चुनाव की घोषणा कर दी। सिंह के तीमरी बार नेता चुने जाने के बाद वोरा ने फोन पर प्रधानमंत्री को उनकी निजी सचिव के माध्यम से संदेश भेजा—"शैल आई रीच देयर अलांग विद भगतजी अर्ली टु सेवन। ओथ विल बी हियर ८.४५ ए०एम०। इफ यू परमिट मी टु कम देयर अर्ली टु सेवेन विद भगतजी।" (क्या मैं भगतजी के साथ सुबह सात बजे दिल्ली आ सकता हूं। यहां शपथ समारोह आठ बजकर, ४५ मिनट पर है। यदि आपकी अनुमति हो तो भगतजी के साथ सात बजे दिल्ली के लिए चल दूं)।

अकेली पसंद: अंततः १४ फरवरी को अर्जुनसिंह ने मोतीलाल वोरा की अनुपस्थिति, समर्थकों की बधाइयों और प्रशंसकों की जय-जयकार के बीच शपथ ग्रहण की और इस प्रकार वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बननेवाले प्रदेश के पहले राजनेता हो गये। दिलचस्प बात यह रही कि १९८० में सिंह कमलनाथ समर्थक विधायकों के बल पर पहले-पहल मुख्यमंत्री बने थे और १९८५ में तथा इस बार भी उनके चुनाव के समय कमलनाथ विशेष तौर पर मौजदू थे। जहां तक मोतीलाल वोरा के बाद प्रशासन की बागडोर सौंपने का सवाल है, दिग्विजय सिंह से लेकर अजीत जोगी और करीब दर्जन भर चुनिंदा विधायकों व मंत्रियों में से कोई भी इस पद के लिये चुना जा सकता था, लेकिन आलाकमान ने इस बार अर्जुनसिंह के अतिरिक्त किसी और नाम पर विचार ही नहीं किया।

भोपाल में १४ फरवरी की रात को प्रधानमंत्री के एक नजदीकी सांसद ने 'माया' से कहा, "देअर वाज नो अदर च्वाइस', वोरा को तीन साल तक मौका देने के बाद प्रधानमंत्री किसी और 'एक्सपेरीमेंट' (प्रयोग) के मूड में नहीं थे।" यह कथन मुख्यमंत्री के तौर पर अर्जुनसिंह के चयन की पूरी कथा कह देता है। प्रशासन की रेलगाडी को फिर से पटरी पर लाकर रफ्तार देने और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखकर राजीव गांधी के समक्ष मध्यप्रदेश में अर्जुनसिंह से बेहतर कोई और विकल्प नहीं था। किसी नये-पुराने नेता को परखने और जोखिम मोल लेने के बजाय राजीव गांधी ने विभिन्न कसौटियों पर कसे हुए, जांचे-परखे कामकाजी नेता को नेतृत्व सौंपना ठीक समझा। वोरा में शीर्ष नेतृत्व के प्रति निष्ठा तो थी, किंतु वह कौशल नहीं था जो समकालीन समस्याओं से जूझने के साथ-साथ भविष्य का संधान करता हुआ चलता है। इस संबंध में अधिकांश नेताओं ने चुप्पी साधे रखी, किंतु केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया के मौसा और पूर्व इंका सांसद डी०के० जाधव ने 'माया' से कहा, "मैं समझता हूं कि अर्जुनसिंह के आने से मध्यप्रदेश पिछड़ने व विपक्ष की झोली में जाने से बच जायेगा।' सिर्फ वही बिगड़े प्रशासन को सुधार सकते हैं। अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में वह पांच साल राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते रहे थे, लिहाजा उनके अनुभव का फायदा मध्यप्रदेश को नहीं मिल सका-था। अब प्रदेश को उनके तजुर्बे व कौशल का लाभ मिलेगा।"

प्रदेश की राजनीति में अर्जुनसिंह के पुनरागमन से अनेक संभावनाएं उठ खड़ी हुई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नेतृत्व-परिवर्तन ने प्रदेश इंकाध्यक्ष पद से दिग्विजय सिंह की विदाई की जमीन जुटा दी तथा दो दिन बाद ही उनके स्थान पर चंदूलाल चंद्राकर की नियुक्ति की घोषणा हो गयी। कुंवर साहब के पुनरागमन से सहकारिता के बेताज बादशाह सांसद सुभाष यादव समेत अन्य

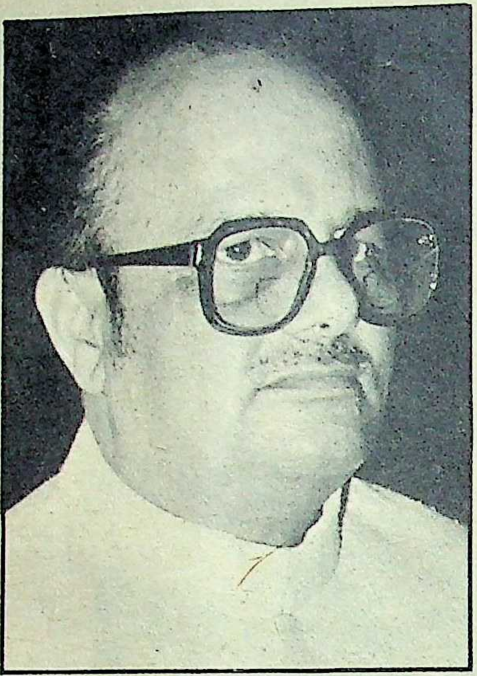

साक्षात्कार/अर्जुन सिंह

अपने नेता की गरिमा बढ़ाऊंगा

देश भर के चतुरतम राजनीतिज्ञों में से एक अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में तीन बार मुख्यमंत्री की गद्दी संभालनेवाले अकेले नेता हैं। लगभग तीन दशकों का उनका राजनीतिक सफर बहुत ही सफल माना जा सकता है। १९५२ में छात्रसंघ का चुनाव जीतने के बाद वह एक भी चुनाव नहीं हारे। इसके अलावा अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें प्रदेश और देश स्तर पर जितनी भी जिम्मेदारियां मिलीं, उन्होंने बखूबी निभायीं और हर पद पर अपनी छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री बनने के पहले वह केंद्रीय संचार मंत्री थे और एक यही पद था, जहां वह कुछ कमाल नहीं दिखा पाये। इसकी मुख्य वजह यह थी कि यहां उनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं।

तीन साल पहले (११ मार्च, १९८५) उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। आम तौर पर राज्यपाल का पद चुके हुए लोगों का पद माना जाता है और इसे बतौर सजा के देखा जाता है। लेकिन कुशल प्रशासक और सूझबूझ के धनी अर्जुन सिंह ने वहां भी अपनी दक्षता की छाप छोड़ी। लंबे अरसे से आतंकवाद से पीड़ित पंजाब में शांति बहाल करने के लिए उन्होंने अकाली नेताओं और केंद्र के बीच एक सफल मध्यस्थ की भूमिका निभायी और इसी का नतीजा था पंजाब समझौता। हालांकि इस समझौते को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका, मगर इससे अर्जुन सिंह की रातोरात धाक जम गयी।

पंजाब में उनकी बेहतरीन भूमिका के लिए पुरस्कार स्वरूप उन्हें केंद्र में वाणिज्य मंत्री (नवंबर, ८५) बनाया गया। जल्दी ही उनकी जरूरत कांग्रेस संगठन में महसूस की गयी और उन्हें जनवरी, ८६ में कांग्रेस का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में अभी अस्थिरता जारी थी और उन्हें फिर से (अक्तूबर, ८६) संचारमंत्री के रूप मंत्रिमंडल में ले लिया गया। शायद उनका मन केंद्र से ज्यादा राज्य की राजनीति में लगता था, इसलिए जब-तब उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में दखलंदाजी और वापस लौटने की खबरें उड़ती रहीं। उधर वोरा की छवि भी 'ढीले मुख्यमंत्री' की बनती जा रही थी। वी०पी० सिंह के अभियान के चलते राजीव गांधी को हिंदी भाषी प्रदेशों में अपनी स्थिति भी मजबूत करनी थी। लिहाजा, हाईकमान ने एक बार फिर अर्जुनसिंह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। चेन्ना रेड्डी के बाद वह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बनने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाये गये।

ऐसा नहीं है कि अर्जुन सिंह को यह सब सहज ही मिलता गया। १९७७ में इमरजेंसी के बाद इंका की करारी हार हुई और अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेतृत्व किया। यह उन्हीं की काबिलियत का नतीजा था कि १९७७ के चुनाव में लगभग साफ हो जाने वाली इंका १९८० के चुनाव में जीतकर दोबारा सत्तारूढ़ हो गयी।

खुद को समाजवादी मानने वाले अर्जुन सिंह की छवि गरीबों के हमदर्द की रही है। यद्यपि उनके ज्यादातर कार्यक्रम व्यवहारिक नहीं थे और इनसे दलित वर्ग को सीधा लाभ भी नहीं मिला। "रिक्शा चालक खुद रिक्शा के मालिक होंगे" की घोषणा को भी सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास और राजनीतिक स्टंट माना गया। चुरहट लाटरी कांड, भोपाल गैस त्रासदी जैसे विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं।

"न मैं रोते हुए गया था और न ही हंसते हुए आया हूं। मैंने हमेशा कर्तव्यपालन को प्रधानता दी है।" यह दिलचस्प टिप्पणी अर्जुनसिंह ने १५ फरवरी की शाम वल्लभ भवन में आयोजित प्रेस-वार्ता में तब की, जब एक संवाददाता ने उनसे उनकी पुनरागमन पर अनुभूति जाननी चाही। राजनैतिक दृष्टि से आरोह-अवरोह से भरी हुई अत्यंत नाटकीय और घटनाप्रधान यात्रा तय की है अर्जुनसिंह ने। अर्जुनसिंह अगर राजनीति से रिटायर होने की घोषणा करके भी भोपाल आते, तो विरोधी खेमों में हड़कंप मच जाता, मगर यहां तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर बतौर मुख्यमंत्री आये हैं"—प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता की इस बात में काफी सच्चाई है। इस सर्वाधिक बेचैनी के शिकार समाजवादी फोरम और 'पूर्व विधायक मंच' के कृष्णपाल सिंह, श्रीनिवास तिवारी, विजय पाटनी, हजारीलाल रघुवंशी, डा० भंवर सिंह पोर्ते आदि नेता हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के सहयोगियों का प्रश्न है; अर्जुनसिंह ने मंत्रियों का चयन काफी सूझबूझ से किया है, किंतु रायपुर संभाग से किसी को प्रतिनिधित्व न देने और एकमात्र सिख व अपने ही गुट के तनवंत सिंह कीर को मंत्री न बनाने को काफी आश्चर्य से देखा जा रहा है। १५ फरवरी की दोपहर में मंत्रिपरिषद ने अपनी पहली बैठक में वोरा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और कार्यों की सराहना की। इसी शाम अर्जुनसिंह ने 'माया' से चर्चा की, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी किसी पत्रिका को दी गयी पहली भेंटवार्ता है:

मायाः मध्यप्रदेश के इतिहास में आप पहले राजनेता हैं, जिसने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी बार यह महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हुए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं?

अर्जुन सिंह: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम कांग्रेस संगठन के अनुशासित सिपाही हैं और इस नाते अपने नेता श्री राजीव गांधी के निर्देश पर किसी भी दायित्व को संभालने अथवा बड़े से बडा त्याग करने को हमेशा तत्पर रहते है। मुझे वही अनुभूति हो रही है जो एक अनुशासित सिपाही को होती है कि वह पूरी शक्ति से अपने संगठन की जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का प्रयास करे और अपने नेता की गरिमा को बढ़ाये। यह जो परिवर्तन हुआ है वह केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं हुआ है। हमारे नेता ने संपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य को सामने रखकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ वह परिवर्तन किये हैं, जिनका अपना राजनीतिक महत्व है। जहां तक इतिहास का सवाल है हम अपना कार्य करते हैं और वह अपने महत्व की दृष्टि से इतिहास में अंकित होता रहता है।

मायाः यह धारणा कहां तक सही है कि आपको संभावित मध्यावधि चुनाव को मद्देनजर रखकर प्रदेश की बागडोर सौंपी गयी है?

अर्जुन सिंह: जहां तक संभावित मध्यावधि चुनाव का प्रश्न है, हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मध्यावधि चुनाव का कोई सवाल ही नहीं है। सक्रिय गतिशील और जीवंत राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के परिवर्तन कोई नयी बात नहीं है। जहां जिस किसी पदाधिकारी की आवश्यकता होती है उसे उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पदस्थ किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसे परिवर्तन मध्यावधि चुनाव को मद्देनजर रखकर किये जायें।

मायाः बतौर मुख्यमंत्री अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ढीले-ढाले प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना, गैस पीड़ितों का कल्याण या विकास की योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन?

अर्जुन सिंह: शासन की बागडोर संभालने के साथ हमें सूखा और पीने के पानी के साथ उन्हीं कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है जिनके द्वारा सामाजिक असमानताएं दूर हों और पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुसार प्रदेश और समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। इस कार्य को संपादित करने में जहां कहीं प्रशासन में ढील पायी जायेगी उसे निश्चित दूर किया जायेगा। यह तो आप जानते ही हैं कि जनकल्याणकारी नीतियों को मूर्तरूप देने के लिये स्वच्छ, सक्षम और जनोन्मुखी प्रशासन पहली आवश्यकता है और इस नाते प्रशासन की ओर ध्यान देना भी हमारी प्राथमिकता है। जहां तक गैस पीड़ितों के कल्याण का सवाल है, निश्चय ही हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और हमारा सतत प्रयास रहेगा कि उनके पुनर्वास के लिए उन्हें पूरी-पूरी सहायता मिले। विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके संबंध में हम अपनी वार्षिक योजना के संदर्भ में उनका जायजा लेंगे और ऐसी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन करेंगे, जिन्हें हमारी पार्टी ने प्राथमिकताएं प्रदान की हैं।

मायाः गत वर्ष आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को एक पत्र लिखकर झुग्गी-झोपड़ीवासियों को पट्टा वितरण में हो रही कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी। झुग्गी-झोपड़ीवासियों को पट्टा देने का निर्णय आपका ऐतिहासिक निर्णय था। क्या अब आप तत्संबंधी शिकायतों की ओर विशेष ध्यान देंगे?

अर्जुन सिंह: झुग्गी-झोंपड़वासियों के पट्टा वितरण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को पत्र लिखा था और उन्होंने उन शिकायतों का परीक्षण कराया था और इसकी पूरी जानकारी श्री वोरा ने मुझे दी थी। उसमें यह बतलाया गया था कि पट्टे न मिलने की अधिकतर शिकायतें निजी भूमि से संबंधित हैं और सरकारी भूमि पर पट्टे न मिलने की जो शिकायतें थीं उनका निराकरण कर दिया गया है। झुग्गी-झोपड़ीवासियों को पट्टा देने का निर्णय हमारी पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से अवश्य ही महत्वपूर्ण था। यदि झुग्गी-झोपड़ीवासियों को नियमानुसार पट्टा देने के संबंध में जो भी कठिनाई होगी उस पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा।

> मैंने तो अभी सत्ता की बागडोर संभाली है। तालमेल के संबंध में सुनी-सुनायी बातों के आधार पर कोई मत व्यक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक मुझे स्मरण है स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की शिकायत से इनकार किया है। सत्ता और संगठन प्रशासन तंत्र के दो पहिये हैं, जिनके तालमेल से ही यह तंत्र सुचारु और संतुलित रूप से चल सकता है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच पूरा-पूरा तालमेल रहे, ताकि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर त्वरित और सार्थक अमल हो।

मायाः श्री वोरा के काल में शिकायत रही है कि सत्ता व संगठन में समुचित तालमेल नहीं है। क्या यह सही है और आप सत्ता व संगठन में तालमेल की दिशा में क्या कदम उठायेंगे?

अर्जुन सिंह: बेहतर होता कि आप यह प्रश्न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से करते। मैंने तो अभी सत्ता की बागडोर संभाली है। तालमेल के संबंध में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कोई मत व्यक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक मुझे स्मरण है स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की शिकायत से इंकार किया है। सत्ता और संगठन प्रशासनतंत्र के दो पहियें हैं, जिनके तालमेल से ही यह तंत्र सुचारु और संतुलित रूप से चल सकता है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच पूरा-पूरा तालमेल रहे, ताकि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर त्वरित और सार्थक अमल हो।

मायाः मध्यप्रदेश में जन मोर्चे की सक्रियता के बारे में आपका क्या खयाल है? मोर्चे की काट के लिये आप क्या कदम उठायेंगे?

अर्जुन सिंह: मध्यप्रदेश में जनमोर्चे का कोई अस्तित्व मुझे नजर नहीं आता। अभी तक इस मोर्चे के स्वनामधन्य नेताओं ने जमावड़े कर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की है, किन्तु प्रदेश की जनता इस तरह की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के हथकंडे से पूरी तरह वाकिफ है और उसने तमाशबीन के रूप में ही इन नेताओं का तमाशा ही देखा है। तमाशे का जितना और जैसा असर होता है उससे सभी लोग वाकिफ हैं। इस तरह का न कोई मोर्चा हमारे प्रदेश में है और न उसके लिए किसी प्रकार की काट की जरूरत है।

—सुधीर सक्सेना

सबको न सुनाने की बात: श्रीमती अर्जुन सिंह से कमलनाथ की गुफ्तगू

नेताओं— भगवानसिंह यादव, राधेश्याम शर्मा, सत्यनारायण शर्मा आदि ने चैन की सांस ली है, अन्यथा इन लोगों पर वोरा की नाराजगी के कारण कार्यकाल पूरा होते ही विदा कर दिये जाने का खतरा मंडरा रहा था। यह भी संभावना है कि सिह सरकारी उपक्रमों से कुछ लोगों की छुट्टी कर वहां अपने विश्वसनीय लोगों को पदासीन करें। पूरे आसार हैं कि सिह अपनी परंपरागत रीति-नीति जारी रखेंगे। अपनी इस शैली का परिचय उन्होंने मंत्रिपरिषद के गठन में बरती छंटनी और 'कोम्बिंग' (Combing) से दे दिया है। अर्जुनसिह की नयी टीम पर दृष्टिपात करें, तो साफ है कि उन्होंने विरोधी गुटों के सदस्य मंत्रियों—रामकिशोर शुक्ल, डा० कन्हैया लाल शर्मा, दुर्गादास सूर्यवंशी की छुट्टी कर दी है। मनमाफिक टीम चुनने में किसी तरह का संकोच न बरतते हुए उन्होंने महेश जोशी को छोड़कर सभी राज्यमंत्रियों—हरिहर प्रसाद शर्मा, चंद्र कुमार भनोत, कैप्टन जयपाल सिह, रसूल अहमद सिद्दीकी, रणवीर सिह शास्त्री और झूठ बोले कौआ काटे फेम के विट्ठल भाई पटेल—का पत्ता साफ कर दिया। तेजतर्रार महेश जोशी को निष्ठा न बदलने का ईनाम उन्होंने राज्यमंत्री से काबीना मंत्री प्रोमोट करके दिया। चंद्रप्रभाष शेखर की पुरानी सेवाओं और योग्यता के एवज में उन्हें उद्योग-वाणिज्य का काबीना मंत्री बनाया गया। राज्यमंत्रियों के तौर पर श्रीमती मंजूराय, विष्णु राजोरिया, हसनात सिद्दीकी, राजमणि पटेल, दाऊ हनुमंत सिह, रामजी महाजन और बतौर उपमंत्री रामेश्वर पटेल के प्रवेश से जाहिर है कि मंत्रिपरिषद एकात्म और मुख्यमंत्री की अपनी पसंद का नतीजा है। पूर्व सरकार में माधवराव सिंधिया के दो नुमाइंदे थे। इनमें से केवल एक बालेंदु शुक्ल को शामिल करना और बालेंदु का शपथ न लेना, सिंधिया गुट की हताशा और बेचैनी को व्यक्त करता है, साथ ही यह भी सही है कि शिव प्रताप सिह का पत्ता काटकर सिंधिया गुट की साख को आघात पहुंचाया गया है। जहां तक गुटीय राजनीति के लिहाज से आकलन का प्रश्न है, विद्याचरण शुक्ल के निष्कासन और सेठी के पराभव के बाद प्रदेश में अकेला सिंधिया का ही गुट शेष बचा है, जिससे अर्जुन गुट के संबंध मैत्री और सद्भाव के नहीं हैं। सिंधिया समर्थकों से बरसों से राजनीतिक घमासान में लिप्त अर्जुन समर्थकों के हौसले का पता ग्वालियर में १२ फरवरी को इंका के दो दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह की घटनाओं से लगता है, जिसमें भगवान यादव सिंह ने बालेंदु शुक्ल को सिंधिया की मौजूदगी के बावजूद अध्यक्षता नहीं करने दी और राजीव गांधी जिंदाबाद के नारों को लेकर दोनों गुटों में ख़ासा बावेला मचा।

आम और पर यह माना जा रहा है और 'माया' के समक्ष इसकी पुष्टि अनौपचारिक चर्चा में कई केंद्रीय नेताओं ने भी की कि अर्जुनसिंह को आगामी पूर्वावधि चुनाव में इंका की विजय पताका फहराने के प्रयोजन से मध्यप्रदेश वापस भेजा गया है। वी०पी० सिंह व वी०सी० शुक्ल के दौरे के बाद अनुमान है कि सिंह जनमोर्चा की मध्यप्रदेश, विशेषकर विंध्य व छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक काट कर सकेंगे। कयास और भी हो सकते हैं, परंतु फिलहाल यह सच है कि राज्यों व केंद्र में अलग-अलग दायित्वों के निर्वाह के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अर्जुनसिंह की वापसी से उनके प्रभामंडल में और अधिक वृद्धि हुई है।

पटना में भी सत्ता हस्तांतरण का नाटक उतना ही रोमांचक रहा। बस घंटे भर की मियाद में हवाई अड्डे पर हजारों की भीड़ जुट गयी थी। वह १३ फरवरी की आधी रात का वक्त था। उस रात साढ़े नौ बजे तक पटना के राजनीतिक हल्कों के सभी टेलीफोन दिल्ली में खबर लेने को बेताब थे कि दुबे तो गये, पर आ कौन रहा है? पटना के सभी अखबारों के दफ्तरों में निरंतर दिल्ली से खबर उगल रहे टेलीप्रिंटर पर सब लटके थे। नाम तब तक बिलकुल स्पष्ट नहीं हो सका था। पर पी०टी०आई० देर तक संभावना व्यक्त करती रही कि इंका के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भागवत झा आजाद का नाम बिहार के लिए लगभग तय हो चुका है। घंटे भर से समाचारों की इस अटकलबाजी से ऊबे कई दिग्गज राजनीतिज्ञों ने अपने-अपने सूत्रों से दिल्ली फोन मिलाया। आखिरकार सूचना मिली कि भागवत झा आजाद बिंदेश्वरी दुबे और चार पर्यवेक्षकों—नारायण दत्त तिवारी, दरबारा सिंह, शंकरानंद और नरेश चंद्र चतुर्वेदी सहित ग्यारह बजे सीमा सुरक्षा बल के विमान से विदा हो चुके हैं। आजाद ही नये मुख्यमंत्री तय हुए हैं। उस समय पटना में मौजूद जितने भी मंत्री, विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पूरी बेचैनी से उस विमान की बाट जोह रहे थे। लेकिन विमान दो बजे हवाई अड्डे पर पहुंचा। बिंदेश्वरी दुबे जब विमान से बाहर निकले, तो उनके एकाध विचलित समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाये, पर भीड़ ने जब अनसुनी कर दिया, तो दुबे के चुनिंदा सहयोगी चुप लगा गये। चुपचाप दुबे उतर कर किनारे से निकल गये। फिर उतरे दरबारा सिंह और उनके पीछे भागवत झा आजाद, शंकरानंद और एन०डी० तिवारी। आजाद ज्यों ही नीचे उतरे कि माला से उन्हें लाद दिया गया। जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। बिंदेश्वरी दुबे अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ गये थे। आजाद वहीं लगी एक सफेद एम्बेसडर में बैठ गये। फिर तो गाड़ियों का पूरा कारवां ही चल पड़ा। मुकाम था मुख्यमंत्री निवास। आधी रात गये गाड़ियों की चमकती रोशनी किसी बड़े उत्सव का अहसास करा रही थी। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच कर दो-चार विधायक उल्लसित थे—"फ्रीडम एट मिडनाइट इन बिहार।" तब तक ढ़ाई बज गये थे। मुख्यमंत्री निवास का पूरा निचला हिस्सा खचाखच भरा था। पैंतीस माह पुरानी दुबे सरकार का इस आधी रात में अंत देखने को सब आतुर थे। मुख्यमंत्री निवास की लाबी में बैठक शुरू हुई। बिंदेश्वरी दुबे ने शुरुआत की—"अपने नेता श्री राजीव गांधी की अनुमति से मैंने बिहार इंका विधायक दल के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया है। मैं इस पद के लिए श्री भागवत झा आजाद का नाम प्रस्तावित करता हूं।" धीमी गति के समाचारवाचक की तरह बोल रहे दुबे साफतौर पर आहत दीख रहे थे। दुबे का वक्तव्य समाप्त हुआ कि अनुमोदन करने दुबे काबीना के संसदीय कार्य मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह उठ खड़े हुए। फिर इंका विधायक दल के नये नेता आजाद ने उस बैठक को संबोधित किया। लगभग आधे घंटे में

'आपरेशन मिडनाइट': १३ फरवरी की रात पर्यवेक्षकों के साथ आजाद

तुरतफुरत शपथ ग्रहण: राज्यपाल सुबैय्या आजाद को शपथ दिलाते हुए

ही सबकुछ खतम हो गया

शपथग्रहण सवेरे सात बजे ही होना था, क्योंकि बिंदेश्वरी दुबे को दिन के साढ़े दस बजे तक दिल्ली केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पहुंच जाना था। चार बजे सुबह तक जगे तमाम लोग भला तीन घंटे क्या सोते ! कहीं सात बजे तक नींद न खुल पाये, इस आशंका में सब जगे थे। फिर साढ़े छह बजे से ही राजभवन में गाड़ियों की कतार लगने लगी। सात बजे तक राजभवन का वह भव्य हाल खचाखच भर चुका था। आगे की पंक्ति में बिंदेश्वरी दुबे, दिल्ली से आये चारों पर्यवेक्षक, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि बैठे थे। बहरहाल, कार्रवाई शुरू हुई। शपथ लेकर भागवत झा आजाद बतौर मुख्यमंत्री शपथ पत्र पर जब हस्ताक्षर करने लगे, तभी बिंदेश्वरी दुबे ने घड़ी में पता नहीं क्या सोचकर समय देखा। उस समय ठीक सात बज कर दस मिनट हुए थे। बिंदेश्वरी दुबे इसी समय विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। दुबे और पर्यवेक्षकों को तत्काल दिल्ली निकलना था। लिहाजा, शपथग्रहण खतम होते ही सब बाहर निकले। राजभवन के पोर्टिको में एक दुबे-प्रेमी ने दुबे को गुलाब का फूल भेंट किया, तो दुबे विचलित हो उठे। पास ही खड़े नये मुख्यमंत्री आजाद को उन्होंने गुलाब बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि—'अब यह फूल इन्हें दीजिए।' आजाद हवाई अड्डे तक जाकर सबको छोड़ आये।

अंत की शुरुआत: सचमुच दुबे-गमन का पंद्रह-बीस दिनों का नाटक काफी दिलचस्प रहा। १३ फरवरी तक दुबे बदहवासी में अनगिनत बार दिल्ली भागते रहे। बात पहली फरवरी की है। सहरसा में पूर्व मंत्री स्व० रमेश झा की ६४ वीं जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाना तय था। पर मुख्यमंत्री सहरसा न जाकर चुपचाप दिल्ली निकल गये, तो राजनीतिक हल्कों में यह खबर छिपी न रह सकी। दिल्ली जाने के एक रात पहले बेचैन दुबे अपने प्रधान सचिव सुब्रह्मण्यम के संग हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। रात के तब बारह बज रहे थे। हवाई अड्डे पर गहरा सन्नाटा था। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद अचानक दुबे को क्या सूझी कि वह फिर घर लौट आये और सुबह दिल्ली गये। इधर मुख्यमंत्री निवास दुबे की अचानक दिल्ली यात्रा के समाचार को भरसक दबाने में जुटा था। उस दिन मुख्यमंत्री निवास से अधिकांश लोगों को फोन पर यही उत्तर दिया जाता रहा कि दुबे सहरसा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में गये हैं। मुख्यमंत्री निवास द्वारा दुबे की दिल्ली यात्रा को छिपाने के अथक फूहड़ प्रयास ने पटना में दुबे की छुट्टी की आशंकाओं को और पक्का कर दिया। ४ फ़रवरी को फिर दुबे वार्षिक योजना का फैसला करने और बाणसागर नियंत्रण परियोजना की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। दुबे समर्थकों ने तर्क देना शुरू किया कि अगर दुबे जानेवाले होते, तो वार्षिक योजना पर परामर्श ही जाकर नहीं करते। पर इन सब फुलझड़ियों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा था। ४ फरवरी को दिल्ली में मौजूद दुबे बेहद उद्विग्न थे। उन्होंने बिहार भवन में मिलने आये पत्रकारों से कहा कि उनके हटाये जाने की बातें महज दुष्प्रचार हैं। पर अकेले दुबे ही बार-बार अपने इस्तीफे की बात का खंडन किये जा रहे थे। ऐसे मौकों पर लपक कर बयान देनेवाले इंका महामंत्रियों की जमात चुप्पी साधे हुई थी। यह संदेहों को मजबूत कर रहा था। हां, पटना के राजभवन से यह खंडन जरूर किया गया कि राज्यपाल द्वारा दुबे से इस्तीफा मांगे जाने की खबर बेबुनियाद है। ५ फरवरी को दुबे दिल्ली में इंका के तमाम भाग्यविधाताओं के यहां अपनी रक्षा की फरियाद लेकर भटक रहे थे। पर सभी जगह उन्हें ठंडा व्यवहार ही मिला। इंका के खजांची सीताराम केसरी जोर-शोर से दुबे की रक्षार्थ 'लाबी' में भिड़े थे। पर व्यर्थ। ५ फरवरी को ही दिल्ली पहुंचकर विक्षुब्ध नेता डा० जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दुबे को हर हाल में अपदस्थ करने की प्रधानमंत्री से मिन्नत की। इधर दुबे की लुटिया डूबती देख बिहार इंका अध्यक्ष डूमर लाल बैठा ने भी दुबे की मुखालफत शुरू कर दी। सांसद तपेश्वर सिंह, कृष्णप्रताप सिंह आदि की चर्चित 'सहकारिता लाबी' भी दुबे की दयनीय स्थिति देख साफ चुप लगा

साक्षात्कार/भागवत झा आजाद

गलत तत्वों से निर्मम सलूक होगा

बिहार के अठारहवें मुख्यमंत्री ६४ वर्षीय भागवत झा आजाद जहां अपनी साफगोई और अक्खड़पन के लिए चर्चित रहे हैं वहीं उनमें संवेदना की गहरी हार्दिकता भी है। संवेदना, बेबाकी, अक्खड़पन आज की राजनीति के शब्दकोष से बाहर हैं। इस लिहाज से आजाद आज की राजनीति में अपवाद हैं। यही आजाद का विशिष्ट आकर्षण भी है। कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से आज बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे आजाद के इस सुदीर्घ राजनीतिक जीवन का बस एक ही प्राणतत्व रहा—अजेय स्वाभिमान! आजाद एक अच्छे कवि भी हैं, पर राजनीतिक आजाद और कवि आजाद के रूप अलग-अलग नहीं हैं। समस्या ग्रस्त प्रांत बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वह अपने सख्त स्वाभिमान और विह्वल संवेदना से हर मोर्चे पर निपटने की तैयारी में हैं। पेश हैं आजाद से 'माया' की बातचीत के अंश:

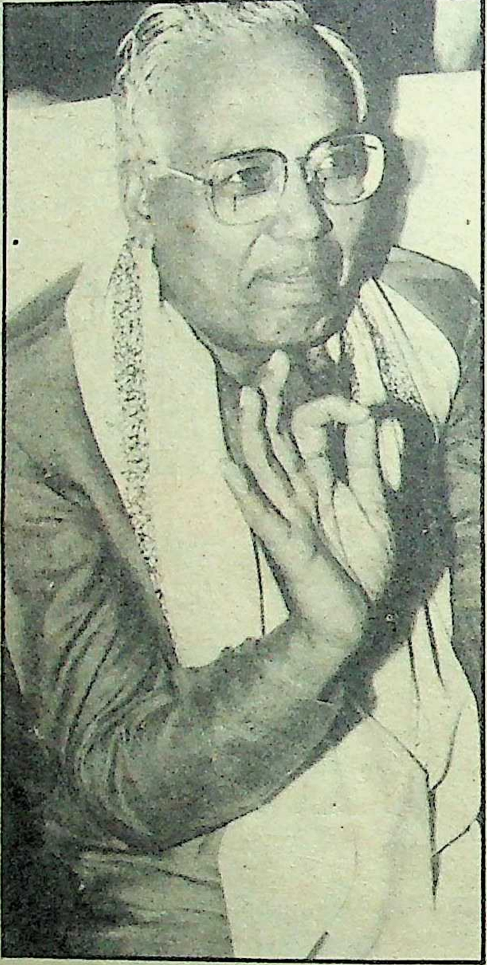

माया: आपको विरासत में सिर्फ समस्याएं ही मिली हैं। तबाहियों से हर स्तर पर टूट चुके इस प्रांत को आप कैसे उबारेंगे?

आजाद: मैं कोरे दावों में विश्वास नहीं रखता। किसी भी कार्य का परिणाम ही असली कसौटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना होगा और प्रशासन के प्रति लोकआस्था को स्थापित करना होगा। यह बिहार की जनता के सहयोग बिना संभव नहीं है। हर बिहारी को आज पूरी शिद्दत और तड़प के साथ बिहार की गरिमा को फिर से बहाल करने के लिए आगे आना होगा। इसलिए अधिकारी, आमजनों और विपक्ष का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। हमारे नेता श्री राजीव गांधी बिहार के लिए बहुत चिंतित हैं। वह बिहार को एक सर्वोन्नत प्रांत के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। हम सबको मिलकर समृद्ध बिहार बनाने की कारगर पहल करनी है। रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हमारे प्रमुख चार मुद्दे हैं। कार्यक्रम को सख्ती से कालबद्ध करना होगा। प्रदेश के आर्थिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हर तीन महीने पर की जायेगी। अगर किसी स्तर पर विकास कार्यक्रमों के अमल में तनिक भी ढील पायी गयी, तो दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

माया: बिहार में नक्सली-उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। आप इन्हें कैसे रोकेंगे?

आजाद: उन इलाकों में जहां उग्रवादी सक्रिय हैं, जनता का विश्वास अर्जित करके इसे रोका जायेगा। पुलिस के बल पर इसे थोड़े दिनों के लिए दबाया जा सकता है, पर जनविश्वास के जरिये इसे हरदम के लिए खतम किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी सोचने की है कि चंद जिलों को छोड़ बिहार के अन्य हिस्सों में ऐसी गतिविधियां नाममात्र को भी नहीं हैं। क्या सामाजिक आर्थिक समस्या के अतिरिक्त भी कोई समस्या है जिससे ये जिले परेशान हैं, इसे भी गौर से देखना होगा। इन हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने के अलावा सांस्कृतिक जागरण भी लाना होगा।

माया: कितनी सरकारें आयीं और गयीं, पर धनबाद का माफिया अपनी जगह अडिग रहा। आप माफिया से कैसे निपटेंगे?

आजाद: माफिया की ताकत प्रशासन से ज्यादा नहीं हो सकती। कोयलांचल के मजदूरों के कल्याणार्थ हम कृतसंकल्प हैं। आतंक और दमन का और अधिक खेल कोयलांचल में नहीं चलेगा। हम माफिया से कैसे निपटेंगे, यह लोग देखेंगे। मैंने पहले ही कहा सिर्फ दावे करने में मेरा विश्वास नहीं।

माया: बिहार राजनीति में कोपरेटिव माफिया की अहम भूमिका रही है। आप कोपरेटिव माफियों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे?

आजाद: दृढ इच्छाशक्ति और ईमानदार नीयत से हर चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। बिहार में सहकारिता जगत में एक नयी सुंदर परपरा की शुरुआत की जायेगी जिससे सहकारी आंदोलन में बिहार अग्रणी रहे। मैंने पहले ही कहा कि मुझे किसी से कोई चंदे की दरकार नहीं। चंदा और थैली की राजनीति मेरे सामने नहीं चलेगी। घूस देनेवालों और लेनेवालों दोनों पर कार्रवाई की जायेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रदेश के क़िसानों को भरपूर खाद, बीज और सिचाई की सुविधा नियमितरूप से सुलभ करायी जाये।

माया: झारखंड समस्या भी सुलग रही है, इसका आप कैसे मुकाबला करेंगे?

आजाद: मैं इस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। आदिवासी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। समाजद्रोही ताकतें उन्हें देर तक बरगला कर नहीं रख सकतीं। आदिवासी अंचल में सघनरूप से विकास अभियान चलाया जायेगा। इतना ही नहीं इस सूबे के हरिजन और अल्पसंख्यक भी अपने जायज हकों से कारगर तौर पर लैस किये जायेंगे।

माया: बिहार के सभी विश्वविद्यालय बीमार हैं। शैक्षणिक वातावरण की वापसी कैसे संभव होगी?

आजाद: इसके लिए छात्र और शिक्षक दोनों का आत्मीय समन्वय किया जायेगा। परीक्षाएं नियमित होंगी। हर वर्ष की निश्चित तिथि पर परीक्षाएं ली जायेंगी। उस तिथि को मुख्यमंत्री से लेकर वाइसचांसलर तक कोई नहीं बदलेगा। बिहार के छात्र बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, पर अनियमित सत्र के कारण वे पीछे रह जाते हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं रहने दी जायेगी।

माया: बिहार में अरसे से चले आ रहे पदस्थापन और स्थानांतरण के राजनीतिक व्यवसाय को क्या आप ठीक कर सकेंगे?

आजाद: जो भी व्यक्ति ऐसे काम लेकर आयेगा उसी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ट्रांसफर-पोस्टिंग की पैरवी के दिन अब लद गये। ऐसे पैरवीकारों से अब निर्मम सलूक होगा।

—विकास कुमार झा

साथ न निभाने का वादा ! : आजाद और दुबे, बीच में नारायण दत्त तिवारी

गयी। इधर मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली से पटना तक अनगिनत नाम गूंज रहे थे। बलिराम भगत, भीष्मनारायण सिंह, शिवचंद्र झा, रामशरण सिंह, सिद्धेश्वर प्रसाद, लहटन चौधरी आदि कई नाम राजनीतिक हल्कों में डूब-उतरा रहे थे। तभी अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद राजीव गांधी से खिन्न चल रहे अब्दुल गफूर भी अपना दावा लेकर मंच पर कूद पड़े। इसी बीच दिल्ली प्रवास कर रहे डा० जगन्नाथ मिश्र को भी अचानक क्या सूझी कि उन्होंने भी अपना दावा पेश कर दिया। जगन्नाथ मिश्र इस तर्क के साथ लाबी कर रहे थे कि अगर राजस्थान में शिवचरण माथुर की वापसी हो सकती है, तो बिहार में उनकी क्यों नहीं। पर जगन्नाथ मिश्र की इस गलतफहमी पर राजनीतिक पंडित चकित थे। इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में जगन्नाथ मिश्र ने पटना में वी०पी० सिंह का स्वागत कराकर सबसे भारी भूल की। यही वजह है कि इंका आलाकमान आज तक उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा।

डा० मिश्र की मात: सचमुच इस बार जगन्नाथ मिश्र के लिए आखिरी बाजी थी जो वह हार गये। वह इस बार एक संग कई पदों के दावेदार थे मसलन, मुख्यमंत्री, केंद्रीय काबीना मंत्री, बिहार इंका अध्यक्ष, इनमें से कोई भी एक पद उन्हें मिलेगा ही, इसके लिए वह आश्वस्त थे। पर मिश्र को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। ५ फरवरी को दिल्ली से पटना लौटे मिश्र फिर ७ फरवरी को दिल्ली पहुंचे। अपनी मुहिम में वह दोबारा सक्रिय हुए, पर उनके सामने स्थिति स्पष्ट कर दी गयी कि बिहार में उन्हें कोई पुनर्वास नहीं मिलने जा रहा। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए जब आजाद का नाम पूछा गया, तो मिश्र ने कड़ा विरोध किया। १३ फरवरी की शाम सात बजे तक मिश्र ने आजाद के नाम की अहर्निश मुखालफत की। पर उन्हें मायूसी ही मिली। शनिवार की उस आधी रात जब आजाद पर्यवेक्षकों सहित पटना के लिए विदा हो रहे थे कि इंका आलाकमान ने चंद आशंकाओं के तहत यह कहकर कि आपसे कुछ बातें करनी हैं, जगन्नाथ मिश्र को दिल्ली में ही रोक लिया। मिश्र भी इस गलतफहमी में रुक गये कि शायद कल केंद्रीय काबीना के शपथग्रहण में उन्हें भी शामिल कर लिया जाये। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। १४ फरवरी की शाम जब मिश्र ने बयान दिया कि नये मुख्यमंत्री को उनका हरसंभव सहयोग मिलेगा। पर भीतर ही भीतर मिश्र घायल थे, क्योंकि बिहार में उनकी मर्जी के खिलाफ बात हुई और तिसपर उनके जानी दुश्मन बिंदेश्वरी दुबे को केंद्रीय काबीना मंत्री-पद दिया गया। दरअसल दुबे को जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही त्यागपत्र देने के लिए तैयार रहने को कह दिया गया था। दुबे कुनमुनाये जरूर पर हरिदेव जोशी का हश्र वह देख चुके थे। आसानी से इस्तीफा देने के कारण ही दुबे को दिल्ली में पुनर्वास भी मिल गया।

१९५२ से लोकसभा के सदस्य रह चुके भागवत झा आजाद का बिहार का मुख्यमंत्री होना कई मायने में महत्वपूर्ण है। आजाद मैथिल ब्राह्मण हैं। लिहाजा, वह भागलपुर से लेकर दरभंगा—मधुबनी यानी मिथिलांचल तक में जगन्नाथ मिश्र के प्रभाव को क्षीण कर सकने में कारगर होंगे। मैथिल ब्राह्मणों का सौ फीसदी समर्थन जगन्नाथ मिश्र के लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा है। पर आजाद के मुख्यमंत्री बन जाने से मैथिल ब्राह्मणों को मरहम लगा है। दुबे मैथिल ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए मिश्र मिथिला में इसका लाभ उठाते थे। पर अब यह उनके लिए कष्टप्रद होगा। आजाद के खिलाफ विक्षुब्ध गतिविधियों की संभावना भी नगण्य इसलिए प्रतीत होती है, क्योंकि एलानिया तौर पर सभी विधायक इससे वाकिफ हैं कि अगले चुनाव में आजाद ही टिकट बांटेंगे। ऐसे में भविष्य में कभी भी उनके विरुद्ध कोई भी गतिविधि घातक होगी। बिंदेश्वरी दुबे आजाद को विरासत में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं दे गये हैं। झारखंड आंदोलन, नक्सली गतिविधि, आसमान छूता अपराध, जकड़ी हुई नौकरशाही, तिकड़मी राजनीति, बीमार विश्वविद्यालय, किसानों का गला दबानेवाली सहकारी लाबी और बिलकुल खोखला मृतप्राय प्रदेश का कांग्रेस संगठन। इन सबसे निपटते हुए आजाद को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभाई सीटों वाले इस प्रांत में कांग्रेस की चुनावी जीत का भी इंतजाम करना है। आजाद दबंग हैं और ६४ वर्ष की इस उम्र में अप्रत्याशित रूप से उत्साही भी। फिर भी देखना है कि इन चुनौतियों का मुकाबला वह किस तरह करते हैं।

छाया: अशोक वाही, प्रभाकर,
गोपाल संगर, आर०सी० साहू

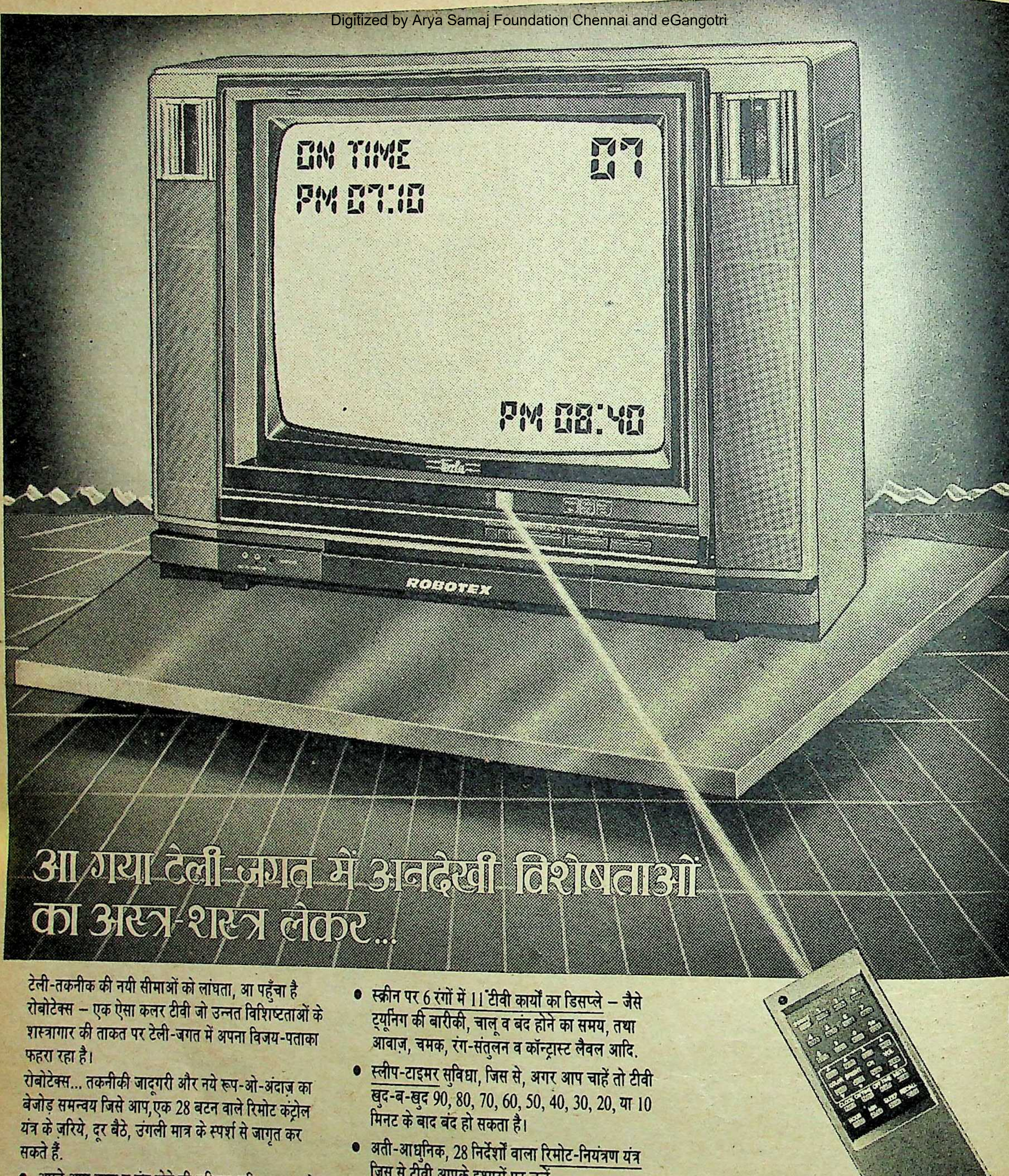

आ गया टेली-जगत में अनदेखी विशेषताओं का अस्त्र-शस्त्र लेकर...

टेली-तकनीक की नयी सीमाओं को लांघता, आ पहुँचा है रोबोटेक्स – एक ऐसा कलर टीवी जो उन्नत विशिष्टताओं के शस्त्रागार की ताकत पर टेली-जगत में अपना विजय-पताका फहरा रहा है।

रोबोटेक्स... तकनीकी जादूगरी और नये रूप-ओ-अंदाज़ का बेजोड़ समन्वय जिसे आप, एक 28 बटन वाले रिमोट कंट्रोल यंत्र के ज़रिये, दूर बैठे, उंगली मात्र के स्पर्श से जागृत कर सकते हैं।

- अपने आप चालू व बंद होने की सुविधा ताकि आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखना न भूलें.
- स्क्रीन पर सुबह-शाम का वक्त दर्शाने वाला विशेष डिजिटल घड़ी.
- स्क्रीन पर 6 रंगों में 11 टीवी कार्यों का डिसप्ले – जैसे ट्यूनिंग की बारीकी, चालू व बंद होने का समय, तथा आवाज़, चमक, रंग-संतुलन व कॉन्ट्रास्ट लैवल आदि.
- स्लीप-टाइमर सुविधा, जिस से, अगर आप चाहें तो टीवी खुद-ब-खुद 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, या 10 मिनट के बाद बंद हो सकता है।
- अती-आधुनिक, 28 निर्देशों वाला रिमोट-नियंत्रण यंत्र जिस से टीवी आपके इशारों पर चले.
- दो-तर्फ़ा डबल स्पीकर.
- पैनल-लॉक, जिसके प्रयोग से आप पूर्व-व्यवस्थित कंट्रोल्स को अनचाहे छेड़-छाड़ से सुरक्षित कर सकते हैं.

naa/ND/TX-88

रोबोटेक्स

...कुछ ख़ास, कुछ अलग!

Texla®
सही पसंद

डा० बासु घोष की मौत

हत्या या आत्महत्या ?

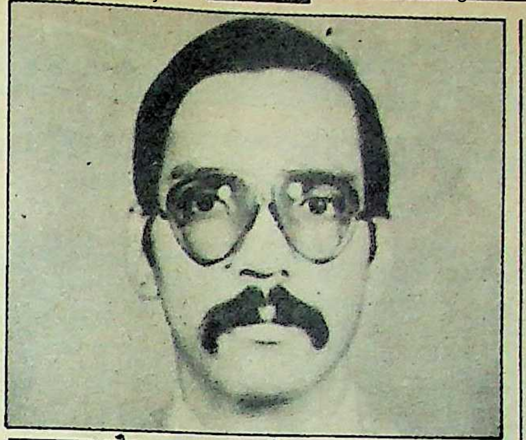

रहस्यमय मौत : डा० बासु घोष

यों तो इलाहाबाद शहर में प्रतिदिन एक-दो हत्याएं या अस्वाभाविक मौतें होती ही रहती हैं और यह इस शहर में रोजमर्रा का सिलसिला बन चुका है। इसलिए न तो इलाहाबाद-वासी चौंकते हैं और न ही पुलिस व प्रशासन के कान खड़े होते हैं। लेकिन गत सात फरवरी को सुबह नैनी रेलवे स्टेशन से दो फर्लांग आगे मिली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के युवा चिकित्सक डा० बासु घोष की क्षत-विक्षत लाश ने इलाहाबाद शहर में हंगामा मचा दिया। चक्का जाम व रेल रोको आंदोलन हुए। दस दिनों तक नैनी औद्योगिक क्षेत्र अशांत रहा और अकेले इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को तीन करोड़ का नुकसान पहुंचा। डा० घोष के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर इलाहाबादवासियों और स्थानीय समाचार पत्रों ने पुलिस और प्रशासन की अच्छी खबर ली, तथापि डा० घोष की मौत के रहस्य से परदा नहीं उठ सका।

संदेह ही संदेह : रेल-पटरी पर डा० घोष का शव देखते ही आई०टी०आई० के कर्मचारियों में खुसफुसाहट शुरू हो गयी कि डा० घोष की हत्या हुई है और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए हत्या के बाद शव को रेल से कटने के लिए रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया। इससे अलग कोई बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। युवा शल्य चिकित्सक डा० घोष बड़े मनोयोग से टेलीफोन इंडस्ट्रीज के मरीज कर्मचारियों का इलाज करते थे। उनकी बोली में मिठास थी। लोकप्रिय, हंसमुख, मेहनती और सुदर्शनीय डा० घोष का भविष्य अनेक संभावनाओं से युक्त था, फिर वह आत्महत्या क्यों करेंगे? वह चिकित्सक हैं, अतः यदि उन्हें आत्महत्या ही करनी होती, तो वह जानते थे कि कौन सा इंजेक्शन या ड्रग लेने से दर्दरहित शांत मौत हो सकती है, फिर आत्महत्या के लिए वह रेल से कट मरने का दर्दनाक रास्ता क्यों चुनते? इन सवालों का उत्तर किसी को नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे सर्वप्रिय चिकित्सक की हत्या आखिर कौन और क्यों करेगा? इसका जवाब अनेक लोगों के पास था। यह चर्चा सरगर्म थी कि डा० घोष के टेलीफोन इंडस्ट्रीज में आने के पूर्व इंडस्ट्रीज के सी०एम०ओ० (मुख्य चिकित्साधिकारी) अधिकांश रोगियों को इलाज के लिए शहर के अनेक 'प्रायवेट नर्सिंग होम' को भिजवा देते थे, जिससे प्रायवेट नर्सिंग होम चलानेवालों को भी मुनाफा होता था और सी०एम०ओ० साहब को भी अच्छा कमीशन मिल जाता था। डा० घोष के आने से अधिकांश मरीजों का इलाज इंडस्ट्रीज के चिकित्सालय में ही होने लगा और उक्त लोगों की कमायी पर पानी फिर गया। यह भी अफवाह उड़ी कि सी०एम०ओ० साहब ने आई०टी०आई० की स्टेट बैंक शाखा से कुछ दिनों पूर्व सत्तर हजार रुपए निकलवाये थे, जिन्हें हत्यारों को डा० घोष की हत्या करने के लिए दिया गया था।

बाद की जांच से उक्त सरगर्म चर्चाएं और अफवाहें निराधार लगने लगी थीं। आई०टी० आई० अस्पताल के रिकार्ड से पता चला कि डा० घोष के आने के बाद इंडस्ट्री के अस्पताल में हुए आपरेशनों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी। १९८४ में वहां १३९, १९८५ में १८७, १९८६ में १४६ और डा० घोष के कार्यकाल के दौरान १५६ आपरेशन हुए थे। दूसरी ओर आई०टी०आई० की स्टेट बैंक शाखा के खातों से पता चला कि सी०एम०ओ० साहब ने फरवरी में कोई बड़ी रकम बैंक से नहीं निकाली। उन्होंने १५ हजार रुपए बैंक से जरूर निकाले थे, लेकिन वह नवंबर १९८७ की बात थी। लेकिन नैनी औद्योगिक क्षेत्र में कोई 'हत्या' के अलावा किसी और संभावना को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी दिन शाम को डा० घोष के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर मृत्यु के बाद का कोई घाव नहीं पाया गया। मतलब साफ था कि रेल से कटने के पूर्व उनकी मौत नहीं हुई थी अर्थात् उन्हें मारकर रेलवे लाइन पर नहीं फेंका गया था, मगर टेलिफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी इस रिपोर्ट को सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी नजर में कुछ असरदार लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पक्षपात कर सकते थे। अतः उन्होंने अगले दिन डा० घोष के शव का पुनः पोस्टमार्टम करवाने की मांग की और अपनी मांग के समर्थन में पांच घंटे तक नैनी औद्योगिक क्षेत्र में चक्का जाम रखा। डा० घोष के पिता एस०के० घोष भी तब तक कलकत्ते से यहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भी दुबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। लिहाजा डा० घोष के शव का ९ जनवरी को दुबारा पोस्टमार्टम हुआ। चिकित्सकों (डा० एस०एन० सिन्हा, डा० निसार अहमद, डा० पी०सी० अग्रवाल तेजबहादुर सप्रू अस्पताल) ने जो रिपोर्ट दी उसने तो हंगामा ही मचा दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार सात प्रमुख घाव जानलेवा सिद्ध हुए थे तथा तीन घाव मृत्यु होने के बाद के थे। जानलेवा सात प्रमुख घाव भी धारदार हथियार की वजह से हुए थे। इस प्रकार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मौत को साफ-साफ हत्या का मामला बता रही थी। इस रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता था कि डा० घोष की हत्या छुरा घोंप कर की गयी थी और बाद में उनका शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था। 'दूसरे पोस्टमार्टम' की रिपोर्ट के उद्घाटित होते ही एक बार फिर सारा नैनी औद्योगिक कांप्लेक्स अशांत हो गया। हजारों लोगों ने दाह संस्कार के समय 'कातिलों को गिरफ्तार करो' की आवाज बुलंद की। प्रायः अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान अनेक दिनों तक बंद रहे, नुक्कड़ सभाएं हुईं, १३ फरवरी को 'रेल रोको' आंदोलन हुआ। औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी सी०बी०आई० जांच की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करवाई गयी सी०आई०डी० जांच से वे संतुष्ट नहीं थे।

डा० घोष के क्षत-विक्षत शव को सबसे पहले सुबह करीब सवा सात बजे रेलवे लाइन की जांच पर निकले एक रेलवे कर्मचारी ने देखा था। मृतक का लहुलुहान सिर धड़ से कुछ दूरी पर पड़ा था। शरीर के अन्य अंग तो वहां थे, लेकिन बांया हाथ गायब था। शव की शिनाख्त करनेवाला पहला व्यक्ति टेलीफोन इंडस्ट्रीज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामानंद था। डा० घोष की जेबों की तलाशी में मिली एक पर्ची रहस्यमय थी। इसमें अंग्रेजी में लिखा था, "दुर्घटना होने की स्थिति में कृपया श्रीमती तुषारिका, ४६ आफिसर्स कालोनी, आई०टी०आई नैनी और मिस्टर एस०के० घोष, १४/१० नंदलाल चटर्जी लेन, सांत्रा गाछी, हावड़ा को सूचित किया जाये।"

क्या डा० घोष को पहले से ही किसी दुर्घटना की आशंका थी? टेलीफोन इंडस्ट्रीज के मेन गेट के गार्ड सुधाकर धनीराम पाढिल के अनुसार उसने डा० घोष को उस दिन सुबह पांच बजे मेन गेट से निकलकर रेलवे लाइन की ओर जाते देखा था। तो क्या डा० घोष किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे थे या ऐसी जगह जा रहे थे, जहां उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी? यदि उन्हें आत्महत्या ही करनी थी, तो उन्होंने पर्ची में साफ-साफ 'दुर्घटना' शब्द के बजाय 'आत्महत्या' शब्द क्यों नहीं लिखा?

मौत का दूसरा पहलू : एक ओर इलाहाबाद-वासी और यहां के दैनिक पत्र इस मौत को हत्या मानकर अपराधियों को पकड़ने में ढिलाई बरतने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर छींटाकशी कर रहे थे, तो दूसरी ओर जांच में एक-के बाद-एक जो तथ्य सामने आ रहे थे, वे 'हत्या' की धारणा पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे थे।

डा० घोष के शव की जेब में से मिली पर्ची पर जिन श्रीमती तुषारिका का नाम-पता लिखा था, वह उनके पड़ोसी ४६ वर्षीय इंजीनियर चिन्मय

जो प्रमुख टू-व्हीलर निर्माताओं की पसंद है
आप भी वही टायर्स चुनिए

TVS
SRICHAKRA

मौलिक साधन पसंद करने वाले भारत के सभी प्रमुख टू-व्हीलरों के लिए. ज़्यादा सुरक्षा और भरोसेमंद पकड़ के लिए मज़बूत बनाए गए.

सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टायर. श्रीचक्रा बनाने वाले हैं टी वी एस - 'ऑटो एन्सीलियरीज़' में जाना-माना एक विश्वसनीय नाम.

भारत के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ख़ासतौर से बनाए गए. श्रीचक्रा टायर ऐसी अनोखी खूबियों से बने हैं जो आपको दें उत्तम कार्यकुशलता और ज़्यादा माइलेज. साथ ही रीट्रेडिंग के लिए इसमें कमाल की गुंजाइश है.

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख टू-व्हीलर निर्माता टी वी एस श्रीचक्रा ही पसंद करते हैं.

STL 5453 HN

TVS SRICHAKRA
TYRES

कांजीलाल की पत्नी हैं। दूसरा नाम-पता उनके हावड़ा निवासी पिता का था। डा० घोष की जेब से आफीसर्स कालोनी स्थित ३७ नबंर के उनके मकान की चाभी भी मिली। चिन्मय कांजीलाल को जब डा० घोष की मौत की खबर दी गयी, तो वह सकते में आ गये। उन्होंने डा० घोष को अपना ऐसा मित्र बताया, जिन्हें वह अपने परिवार का सदस्य मानते थे।

टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कुछ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ जब पुलिस ने डा० घोष का घर उनके शव से मिली चाभी से खोला, तो अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक सूटकेस ने सारे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उस सूटकेश पर भी एक पर्ची और सूटकेस की चाभी रखी थी। पर्ची में बंगला में लिखा था कि इस सूटकेस को श्रीमती चिन्मय कांजीलाल (श्रीमती तुषारिका) ही खोलें। श्रीमती कांजीलाल ने जब वह सूटकेस खोला, तो उसमें जनाने कपड़े और वे सामान मिले, जिनका प्रयोग सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। वहां एक चश्मा भी मिला जिसे आश्चर्यचकित होकर देखते हुए श्रीमती कांजीलाल ने स्वीकार किया कि यह उनका है। पुलिस को घर की तलाशी में एक कमीज भी मिली जिस पर खून के दाग थे, एक बटन टूटी (झटके से) हुई थी और कमीज का बायां बाजू आगे से काटा हुआ प्रतीत होता था।

हत्यारों को पकड़ो: अशांत इलाहाबादवासियों द्वारा रेल रोको आंदोलन

डा० घोष अविवाहित थे, अकेले रहते थे। उनके कमरे में महिलाओं के वस्त्रों से युक्त सूटकेस कहां से आया? श्रीमती कांजीलाल का चश्मा उसमें क्यों था? आदि सवालों का जवाब तलाशते हुए जो तथ्य सामने आये वे डा० घोष की मौत के रहस्य को और गहरा कर रहे थे।

हावड़ा (कलकत्ता) में १७ नवंबर १९५९ को जन्मे डा० घोष ने क्रिश्चियन मेडिकल कालेज लुधियाना से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और आल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट, दिल्ली से शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा कोर्स किया था। उनके पिता एस०के० घोष फिलिप्स इंडिया, कलकत्ता में इंजीनियर हैं। एक भाई जयघोष कनाडा में वैज्ञानिक, तो दूसरा भाई इंदर घोष चार्टर्ड एकाउंटेंसी में अपना कैरियर बनाने में लगा है। एकमात्र बहन कु० नारायणी घोष ने एम०एससी० की है। इस प्रकार डा० घोष शिक्षित, उन्नत व खाते-पीते परिवार से संबद्ध थे। ३ जनवरीं, १९८७ को उन्होंने आई०टी०आई० में नौकरी शुरू की थी। नैनी आते ही अपने मिलनसार स्वभाव और चिकित्सा कार्य में बढ़ती ख्याति के कारण वह शीघ्र ही आई०टी०आई० के कर्मचारियों खासतौर से आई०टी०आई परिक्षेत्र में रहनेवाले बंगाली परिवारों में हिलमिल गये। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार है, इंडस्ट्री के इंजीनियर चिन्मय कांजीलाल का। डा० घोष उन्हें दादा और उनकी ४० वर्षीय पत्नी श्रीमती तुषारिका को दीदी कहते थे। इस परिवार से डा० घोष के संबंध प्रगाढ़ होते चले गये। श्रीमती तुषारिका के संबंध में डा० घोष के बड़े अच्छे विचार थे। डा० घोष द्वारा अपनी डायरी में लिखे विवरणों से पता चलता है कि इस परिवार से वह प्रतिदिन मिलते थे और श्रीमती तुषारिका और उनके बच्चों के साथ वह सिविल लाइंस आदि घूमने व खरीदारी करने भी जाते थे। २९ जून के पृष्ठ पर डा० घोष ने लिखा था, "दीदी और मैं सिविल लाइंस गये, हमने महसूस किया कि मुझे एक बहन की और दीदी को एक भाई की जरूरत है, वह (दीदी) अद्भुत हैं।"

यही दीदी श्रीमती तुषारिका डा० घोष की राजदां थी। डा० घोष उनसे कुछ छिपाते नहीं थे। डा० घोष ने १७ नवंबर १९८७ को अपने जन्म दिन पर अपनी डायरी में लिखा था कि आज उनका अंतिम दिन था, लेकिन दीदी ने ऐन वक्त पर आकर बचा लिया। इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि डा० घोष में संभवतः ऐसी ग्रंथि घर कर चुकी थी, जो उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करती थी। इसी पांच फरवरी को मौत के दो दिन पूर्व एक बार फिर डा० घोष ने अपने बायें हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और श्रीमती तुषारिका द्वारा उन्हें बचाने की कोशिश में ही डा० घोष के कमीज की बटन टूट गयी थी और यही कमीज पुलिस को डा० घोष के घर की तलाशी में मिली थी। आई०टी०आई० आफिसर्स कालोनी परिसर में रहने वाले एन०के० मुखर्जी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उस दिन सुबह दो बार श्रीमती तुषारिका उनके घर यह कहने भागी-भागी आयीं थीं कि डा० घोष की तबियत खराब है। पहली बार जब श्री मुखर्जी श्रीमती तुषारिका के साथ डा० घोष के घर गये, तो डा० घोष आवेश में थे और ब्लेड से अपने बायें हाथ की नस काटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने श्री मुखर्जी को वापस चले जाने के लिए कहा था, लेकिन दूसरी बार जब वह वहां पहुंचे, तो डा० घोष शांत थे और लेटे हुए थे।

रहस्य गहराया: ये तथ्य संकेत देते हैं कि डा० घोष आत्महत्या के लिए प्रेरित करनेवाली ग्रंथि से ग्रस्त थे और न चाहते हुए भी आत्महत्या करने की इच्छा उनमें जाग्रत हो जाती थी। संभवतः इसी कारण वह स्वयं भी सशंकित रहते हों कि वह अपने साथ कहीं भी कैसी भी दुर्घटना कर सकते हैं। सात फरवरी को बड़े सबेरे घर से निकलते हुए भी क्या वह आशंकित थे कि न चाहते हुए भी वह स्वयं आत्मघाती दुर्घटना में फंस सकते हैं और संभवतः इसीलिए उन्होंने अपनी जेब में रखी पर्ची में 'दुर्घटना' शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन वह सूटकेस और उसमें मिले जनाना वस्त्रों और सामानों का रहस्य अभी अनसुलझा है? वह किसका सूटकेस है और उसमें रखे वस्त्र और सामान किसके हैं? डा० घोष ५ फरवरी से २० दिन के अवकाश पर थे—वह सूटकेस यह संकेत देता है कि डा० घोष उस दिन कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे, लेकिन क्या उनके साथ कोई महिला भी यात्रा पर जानेवाली थी? वह महिला कौन थी? डा० घोष ने उस सूटकेस को श्रीमती तुषारिका द्वारा खोलने का ही निर्देश क्यों दिया था? डा० घोष का शव रेलवे लाइन के डाउन ट्रेक पर था। अर्थात् वह इलाहाबाद से हावड़ा जानेवाली किसी ट्रेन से कटे होंगे। वहां से सुबह सवा पांच बजे से सात बजे के बीच क्रमशः तिनसुखिया, मिलिटरी स्पेशल, ८१६ नबंर की मालगाड़ी व मगध एकसप्रेस ट्रेनें गुजरी थीं। लेकिन उस अवधि में गुजरी उक्त चारों ट्रेनों के किसी ड्राइवर ने अगले स्टेशन पर, किसी व्यक्ति के रेल से कटने अथवा रेल पटरी पर किसी शव के होने की कोई सूचना क्यों नहीं दी? क्या किसी ने डा० घोष की नृशंस हत्या करके उनका क्षत-विक्षत शव मगध एक्सप्रेस के गुजरने के बाद (सात बजे के आसपास) वहां फेंका था? आदि अनेक सवाल डा० घोष की मौत के रहस्य को उलझाते जा रहे हैं। असलियत तो सी०आई०डी० जांच के बाद ही सामने आयेगी, लेकिन इलाहाबादवासियों खासतौर से आई०टी०आई० के कर्मचारियों को इस बात का सदमा पहुंचा है कि एक होनहार, परिश्रमी युवा चिकित्सक डा० घोष को ऐसी हृदय-विदारक मौत मिली।

छाया: वसीमुल हक

—संजीत सिंह

सूखा-राहत की रकम कहां गयी ?

सूखा राहत : धन के पानी से आंकड़ों की सिंचाई

सूखे की भयावहता का काफी प्रचार-प्रसार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से जो रकम ली थी, उसमें से मुश्किल से २० प्रतिशत रकम भी खर्च नहीं की गयी है। इस बाकी बची रकम का क्या होगा ? जो रकम खर्च हुई भी है, क्या उससे सूखा-पीड़ितों को कोई लाभ मिला है ?

सदी के भयंकरतम सूखे की खबरें अब सुर्खियों में नहीं हैं, लेकिन उसकी चोट के घाव अब भी सूखे नहीं हैं। लोगों को यह भी याद है कि हर राज्य ने अभूतपूर्व सूखे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से भारी-भरकम रकम की वसूली की, लेकिन उस रकम का इस्तेमाल कहां और कितना हुआ, यह शायद आम जनता को मालूम नहीं। सूखा राहत कार्यों के लिए किसी रकम का क्या बना, यह जानने के लिए बानगी के रूप में उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया जा सकता है।

सूखे के धुंआधार प्रचार, १२२ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल नष्ट होने और तीन हजार करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले १२०६.४६ करोड़ रुपए और बाद में संशोधित १३१४.११ करोड़ रुपए की मांग केन्द्र सरकार से की थी। इसके एवज में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश को, बकौल मुख्य मंत्री के १४१.५३ करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत दी, जबकि केन्द्रीय ऊर्जामंत्री वसंत साठे का कहना है, "केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में सूखा राहत कार्यों के लिए कुल १५१ करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे।"

पहली जनवरी को राजस्वमंत्री अम्मार रिज़वी ने जो लेखा-जोखा छपवाकर बंटवाया था, उसमें स्वीकार किया गया था कि सरकार केन्द्र से प्राप्त १४१.५३ करोड़ रुपए की धनराशि में से दिसंबर तक कुल १७ करोड़ ७१ लाख रुपए ही खर्च कर सकी। दूसरे शब्दों में कुल राशि का १३ प्रतिशत धन ही उपयोग में लाया जा सका। बाकी रकम का क्या होगा ? जब दिसंबर तक पिछले चार महीनों में १३ प्रतिशत रकम ही खर्च हुई है, तो क्या यह संभव है कि मार्च तक शेष रकम का इस्तेमाल हो जायेगा ? जाहिर है या तो आंकड़ों का झाड़ू सारी रकम पर फेर दिया जायेगा या फिर यह रकम 'लैप्स' हो जायेगी।

लखनऊ में सरकार का निवास है। इस जिले में चल रहे सूखा राहत कार्य को मानदंड मानकर शेष ५५ जिलों के कार्यों को परखा जा सकता है। सूखा राहत के अंतर्गत जिले में कुल १५४ किलोमीटर कच्ची सड़कों के लिए ५२ लाख से ज्यादा रुपए का प्रावधान है। इनमें से मजदूरी के रूप में १२ लाख रुपए का खाद्यान्न देने की व्यवस्था है। इस कार्य को कई एजेंसियां कर रही हैं। इस संबंध में सरोजिनी नगर क्षेत्र के विधायक शारदा प्रताप शुक्ल ने 'माया' को बताया, "सड़क बनाने में विकास खंडों को ३० हजार, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को ४४ हजार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए ५६ हजार रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से धन खर्च करने की व्यवस्था है। लेकिन सार्वजनिक विभाग की सड़कों का कुछ पता नहीं। विकास खण्डों द्वारा बनायी जा रही सड़कों में ग्रामीणों को काम देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि काम ठेकेदारों से कराया जा रहा है जो निर्धारित 'नार्म्स' के खिलाफ है। सरोजिनी नगर, काकोरी, मलीहाबाद, चिनहट और मोहनलाल गंज ब्लाक में इसके कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। मस्टर रोल केवल कागज पर दिखाया जाता है और धन अधिकारियों, ठेकेदारों और मुकामी सरकश लोगों में, जिनमें कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं, बंट जाता है। हाल तो यह है कि सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को

स्वीकृति मिलने के पहले ही उनका निर्माण हो जाता है और फिर अधिकारियों व ठेकेदारों तथा ग्राम प्रमुखों में धन के बंटवारे की व्यवस्था हो जाती है।"

वार्षिक बजट नदारद : मलीहाबाद के ब्लाक प्रमुख आत्मा राम गुप्त कांग्रेसी हैं। उनकी शिकायत है कि गांव विकास के लिए हर ब्लाक को हर साल औसतन १२ लाख रुपए दिये जाते हैं। अब तक कुल पांच लाख रुपए मिले हैं। हमारे बजट का पैसा काटकर सूखा राहत में सड़कें बनवायी जा रही हैं। सूखे का एक भी पैसा नहीं मिला। जितना काम हो रहा है, उससे ज्यादा काम तो हम अपने वार्षिक बजट से ही कर लेते हैं। वार्षिक बजट की फाइल पिछले चार महीनों से दफ्तर में पड़ी है। अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "रूटिंग का ही पैसा दे दें, तो सूखा राहत की जरूरत नहीं। सूखे में न तालाब बन रहे हैं, न खडंजा बन रहा है... कोई काम नहीं हो रहा।"

ब्लाक प्रमुख आगे कहते हैं, "सूखे में तो खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। उसकी भरपाई रबी की फसल में हो जानी चाहिए। इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आलम यह है कि मलीहाबाद ब्लाक में नहर की सफाई तक नहीं हुई है। यहां तक कि राहत में नहर बनाने के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। नलकूप बेकार पड़े हैं। पेयजल के नाम पर स्वीकृत धन तक नहीं उपलब्ध हो सका है।"

मोहनलाल गंज के रसूलपुर गांव के प्यारेलाल यादव ने बताया, "सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बना। कुएं की सफाई भी नहीं हुई है। करोरा माइनर में साल भर से पानी नहीं आ रहा। तमाम परती जमीन पड़ी है। कोई नया ट्यूब वैल नहीं बना। समेसी गांव में दो साल पहले चार सरकारी नलकूप लगे थे। अब तक दो-दो घंटे के लिए भी नहीं चले। हाकिम परगना से शिकायत की गयी, मगर कुछ नहीं हुआ।"

चिनहट ब्लाक के कृपाल सिंह भी ऐसी ही शिकायत करते हैं, "राहत के सिलसिले में एक सड़क बन रही है, लोनापुर से दमरिया तक। मिट्टी पड़ रही है मजदूरी ६ रुपए रोज से ज्यादा नहीं दी जा रही। गल्ला देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहरों में पानी इतना कम आया है कि पानी के लिए कोयाम गांव, हरदासी खेड़ा वगैरह में किसानों में चार-छह जगह फौजदारी हो चुकी है। नगर में ज्यादा पानी होता, तो फौजदारी नहीं होती। अलबत्ता इससे पुलिस की आमदनी बढ़ गयी है।"

भगवान का आसरा: नहरों के बारे में विधायक शारदा प्रताप शुक्ल की राय भी दीगर नहीं है, "जहां तक नहरों की सफाई का सवाल है, सफाई तो हर साल होती है। मगर, पानी कभी नहीं आता जैसे भौकापुर, वेंती, खाण्डेदेव, रहीमपुर पड़ियाना माइनर आदि। इनमें कभी पानी नहीं आता, जबकि सफाई के नाम पर विभागीय अधिकारियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। सूखे में निःशुल्क बोरिंग के नाम पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। बरौना ग्राम सभा के किसानों ने

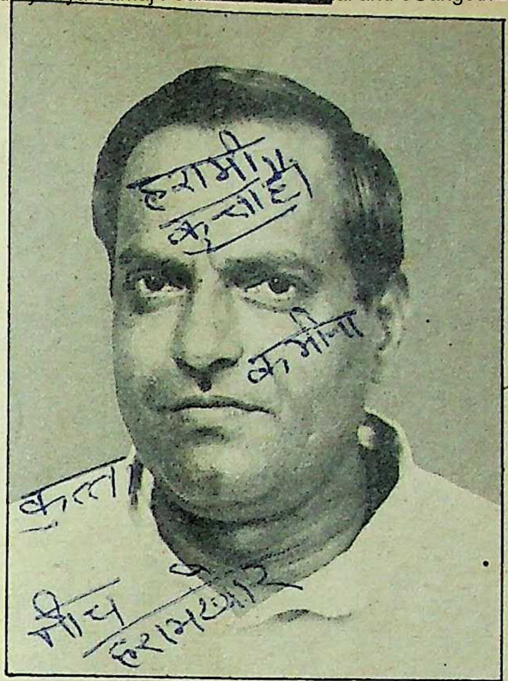

आज के आसफुद्दौला: वीर बहादुर सिंह

जानकारी दी कि उन्हें बोरिंग के लिए ४० फुट पाइप निःशुल्क दिया गया, जबकि ५० फुट पाइप मिलना चाहिए। किसानों को शासन द्वारा तीन हजार रुपए दिये जाने की व्यवस्था है। लेकिन उन्हें मात्र १२०० रुपए का ही पाइप मिल पाता है, शेष धनराशि ब्लाक स्तर पर ही हड़प ली जाती है। किसानों के मांगने पर उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा शेष धन जमानत के रूप में जमा है...सरकार फर्जी आंकड़े पेश करके सूखा राहत के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। गरीब जनता के लिए आवंटित करोड़ों रुपए गोलमाल कर खाये जा रहे हैं। इस देश का तो भगवान ही मालिक है।"

किसान नेता रामकिशोर शर्मा का कहना है—"सूखा राहत के नाम पर केवल सड़कें बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए ग्राम प्रधान से मिलकर ग्राम सेवक को उन्हीं गांवों के किसानों और मजदूरों से काम लेना चाहिए, जिन गांवों में सड़कें बनायी जा रही हैं। मगर ऐसा नहीं हो रहा। मुकामी सरकश ठेकेदार औने-पौने सड़क बनाये जा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए ग्राम सेवक मस्टररोल लेकर इधर-उधर भाग रहा है। निर्धारित साढ़े तेरह रुपए के एवज में मजदूरी पांच-छह रुपए दी जा रही है। इस सिलसिले में जिले के मुख्य विकास अधिकारी को पूरे जिले से पचासों शिकायतें भेजी गयी हैं। कुछ में जांच भी चली। शिकायत सही पायी गयी। मगर मुकामी दबंगई के कारण कुछ भी नहीं हुआ।

अम्मार रिजवी

अजीज जावेद खान

इस सिलसिले में जब 'माया' के प्रतिनिधि ने जिले में राहत कार्यों के तालमेल के लिए जिम्मेदार मुख्य विकास अधिकारी राम प्रताप सिंह से सच्चाई जानने के लिए सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, तो पहले कई दिनों तक मिले ही नहीं। बाद में अपने निजी सचिव आर०एस० वर्मा से कहलवा दिया—"इस बारे में किसी से बात करने का उन्हें अधिकार नहीं है।"

सूखे पड़े नलकूप : सूखे में पानी की अहमियत है। इस बारे में यह दिलचस्प बात सामने आयी कि प्रदेश के डेढ़ लाख नलकूप और हैण्डपाइप इण्डिया मार्क टू में से ८० प्रतिशत बेकार पड़े हुए थे। इसकी एक वजह सरकार का राजनीतिक निर्णय बताया गया। आज से तीन साल पहले जल निगम के जिम्मे ट्यूबवैल और हैण्डपाइप के रखरखाव का काम था। तीन साल पहले सरकार ने निर्णय लिया कि इनके रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग को सौंप दी जाये। यह जाने बगैर कि विभाग के पास इसका तकनीकी ज्ञान और मरम्मत करने वाला अमला है या नहीं, आनन-फानन पंचायतीराज विभाग को यह काम सौंप दिया गया।

नतीजे के तौर पर मरम्मत के अभाव में सारे नलकूप बेकार हो गये। इस सूखे में सरकार की आंखें खुलीं, तो १३ करोड़ रुपए देकर रखरखाव और मरम्मत के काम का जिम्मा फिर जल निगम को दिया गया। अब पूरे प्रदेश में ६० प्रतिशत नलकूप और हैण्डपाइप काम कर रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत राहत पेयजल के मामले में ग्रामीणों को मिल पा रही है।

राहत काम पर अमल किस तरह से हो रहा है, इसका पता खाद पर छूट देने की बात से चल जाता है। बुआई के पहले सुपर फास्फेट और डी०ए०पी० खादों की जरूरत पड़ती है और यूरिया बाद में डाली जाती है। छूट यूरिया में नहीं दी गयी है और छूट की सुपर फास्फेट तथा डी०ए०पी० खाद २० नवंबर तक किसी स्टोर पर उपलब्ध नहीं थी। जब बुआई खतम हो गयी, तो यह खाद स्टोर में आयी। छूट के बावजूद काश्तकारों ने इन खादों को उठाया तक नहीं। इस सिलसिले में एक बात और दिलचस्प है कि छोटे काश्तकारों को १० रुपए बीघे के हिसाब से अधिकतम ४० रुपए और बड़े काश्तकारों को ८० रुपए छूट दी जा सकती है। मगर इसकी औपचारिकता पूरी करने में कम-से-कम तीन दिन लग जाते हैं। नतीजतन छोटे काश्तकारों को ४२ रुपए की मजदूरी का नुकसान होता है। भला ४२ रुपए का नुकसान कर कौन काश्तकार ४० रुपए की छूट और सरकारी अमले की जहमत मोल लेगा? यही नहीं, सरकारी तंत्र ने घोषणा की थी कि १० अक्तूबर तक जो काश्तकार आलू की बुआई करेगा, उसे ६०० रुपए का अनुदान खाद और कीटनाशक दवाओं के रूप में दिया जायेगा। इस पर जिन किसानों ने अमल कर १० अक्तूबर से पहले

बुआई कर दी, उनका सारा बीज सड़ गया, क्योंकि तब तक बेमौसम बरसात हो गयी थी। इस तरह इस योजना से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिन काश्तकारों ने निर्धारित समय के बाद बुआई की, उन्हें समय सीमा का हवाला देकर कोई अनुदान नहीं दिया गया। अनुदानं का सारा स्वरूप कागजी बनकर रह गया।

ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां से सूखा राहत के नाम पर की जा रही घपलेबाजी की शिकायत सरकार तक नहीं पहुंची हो। शिकायत करने वालों में सत्तारूढ़ दल इंका और विपक्ष दोनों शामिल हैं। हर अखबार में मुकामी स्तर पर काम न होने और भ्रष्टाचार की खबरें छपती रही हैं। जिलाधिकारी और जिला विकास अधिकारी के स्तर पर लिखित शिकायतों का अम्बार है। अगर ऐसा मानकर चला जाये कि एक जिले में कम-से-कम ५०० शिकायतें दर्ज करायी गयी होंगी, तो ५० जिलों में शिकायतों की तादाद साढ़े पांच हजार हो जाती है। क्या सरकार ईमानदारी और हिम्मत से दर्ज करायी गयी शिकायतों के आंकड़े उसी तरह पेश करेगी, जिस तरह वह किये गये राहत कामों के आंकड़े पेश कर रही है?

रामकिशोर शर्मा

शारदा प्रताप शुक्ल

विपक्ष का आरोप है कि राहत कार्य संतोषजनक नहीं हुआ है। जिलों में सर्वदलीय समिति भेजकर राहत कार्यों की जांच करायी जानी चाहिए, ताकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो सके। इस बारे में सरकार को श्वेतपत्र जारी करने की चुनौती भी दी गयी है। मजेदार तथ्य यह है कि न तो इंका के पास और न ही विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के पास कोई ऐसा तंत्र है जो सरकारी आंकड़ों पर निर्भर रहे बगैर अपनें कार्यकर्ताओं से काम से आंकड़े इकट्ठा करवा सके। ऐसे आंकड़ों के अभाव में सरकारी तंत्र के आंकड़ों के झूठ या सच को कोई ठोस चुनौती नहीं दी जा सकती। हवाई आलोचना करके सरकार को जनता की निगाह में गिराने के काम से विपक्ष को आत्म संतोष तो मिल सकता है, लेकिन सूखे से पीड़ित जनता को कोई राहत नहीं पहुंचायी जा सकती। उसे तो भले-बुरे दोनों ही रूपों में सरकारी अमले, मुकामी गुण्डों और सरकश लोगों के सहारे ही अपनी जिन्दगी गुजारनी है। दूसरी ओर सरकारी तंत्र, आंकड़ों का जादुई खेल जारी रखती है और हर प्राकृतिकं आपदा के समय करोड़ों रुपयों का हेरफेर हो जाता है।

—अशोक रजनीकर

जिसे न दे मौला ....

अवध के गावों में आज भी एक कहावत मशहूर है—जिसे न दे मौला, उसे दे आसफुद्दौला। बात १७८४ की है। अवध में भयानक अकाल पड़ा। लोग दाने-दाने को मोहताज हो गये। यहां तक कि शहर के समृद्ध लोगों के भी भूखों मरने की नौबत आ गयी। उस समय अवध की गद्दी पर नवाब आसफुद्दौला विराजमान थे। भुखमरी से रियाया को बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने इमामबाड़ा बनाने का एलान किया, ताकि इमारत बनाने के काम में लोग लग सकें और उन्हें उनकी मेहनत के बदले रकम और अनाज मिल जाये। लिहाजा १६७ फुट लम्बी और ५३ फुट चौड़ी इमारत बनना शुरू हो गयी। दिन में गरीब और फाकाकश लोग मेहनत कर मजदूरी पाने लगे और रात के अंधेरे में वे लोग काम करने लगे जो दिन की रोशनी में मजदूरी करने में कतराते थे। दिन में तामीर का काम चलता था और रात में बने हिस्से को गिराने का। इस तरह रात और दिन मजदूरी देकर नवाब आसफुद्दौला ने अपनी रियाया को अकाल के बेरहम पंजे से बचा लिया और एक दिन ऐसी सुंदर और शानदार इमारत बनकर तैयार हो गयी जो आज भी अपने किस्म की बेमिसाल है। आज भी इस इमारत को बड़े इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है। तभी से कहावत मशहूर है—जिसे न दे मौला, उसे दे आसफुद्दौला...

इस किस्से की जानकारी देते हुए मलीहाबाद के नौजवान कम्युनिस्ट नेता अजीज जावेद खान ने कहा, "इस साल प्रदेश में सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। मौला ने तो पानी नहीं बरसाया, लेकिन राहत कार्यों के मामले में आज के नवाब (शासक) आसफुद्दौला की रत्ती भर भी बराबरी नहीं कर सकते। हमने अपनी किशोर अवस्था में एक कहानी पढ़ी थी कि किसी एक जिले को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद एक निलंबित जूनियर इंजीनियर अपने बास के लिए मिठाई का डब्बा लेकर गया। बड़े इंजीनियर साहब को डब्बा थमा कर वह बोला, "बधाई हो सर, इलाका सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। कुछ इस गरीब का भी खयाल कीजिएगा, बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं।" इसके बाद सूखे के नाम पर दोनों बड़ी जोर से हंसे और फिर जाम से जाम टकराने लगे। तब इस कहानी का अन्दरूनी मतलब हमारी समझ में नहीं आया था। लेकिन, सूखा राहत के लिए चलने वाले काम को देखकर अब हम सब कुछ समझ गये हैं। १७८४ के आसफुद्दौला और १९८७ के आसफुद्दौला में यही फर्क है जनाब।

* * *

पास में खड़े किसान सभा के नेता रामकिशोर शर्मा ने जानकारी दी, "मलीहाबाद ब्लाक में हरिजनों की जमीन सींचने के लिए दस साल पहले २६ ट्यूबवेल लगे थे। आज २५ खराब पड़े हैं और एक चल भी रहा है, तो उससे प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री के खेत सींचे जा रहे हैं। अगर मेरी बातों का यकीन न हो, तो संन्यासी बाग जाकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि किस तरह सूखे के इस आलम में हरिजनों को पानी मुहैया कराने वाला ट्यूबवेल आज के आसफुद्दौला (शासक) के खेत की प्यास बुझा रहा है।"

रामकिशोर शर्मा ने काबीना मंत्री का जिक्र बख्शी दीदी (स्वरूपकुमारी बख्शी) के सम्बोधन से किया। आसपास खड़े अन्य गांव वालों ने उनकी बात की तसदीक की। हमारी समझ में तब की कहावत और आज के अमल का फर्क साफ दिखायी पड़ने लगा।

* * *

शर्माजी ने एक और दिलचस्प बात बतायी, "राजधानी के जनपद में मुख्यमंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों की नाक के नीचे केवल २५ किलोमीटर दूर मलीहाबाद कस्बे में सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने के नाम पर दूरदर्शन की एक टीम फिल्म बनाने पहुंची। तहसील स्थित सप्लाई बाबू ने एक दुकान पर पांच बोरा राशन जमा किया और लोगों को पांच-पांच किलो के हिसाब से निःशुल्क बांटने लगा। फिल्म बनने लगी। जैसे ही दूरदर्शन के लोगों ने काम पूरा किया और चलने लगे, वैसे ही लोगों से जबरन राशन वापस ले लिया गया। कुछ गरीब लोग धक्कम-धुक्की में नजर बचाकर निकल लिये। कुछ लोगों ने इस झूठ का परदाफाश करने के लिए परगनाधिकारी से शिकायत की। मगर कुछ नहीं हुआ। बाद में टी०वी० पर देखा कि सरकार सूखे में कितनी अच्छी तरह भूखों का खयाल रख रही है।"

सबसे मजेदार किस्सा इंका के एक मुंहफट सांसद ने सुनाया। उन्होंने कहा, "काफी लंबे समय के बाद जिस दिन अचानक बारिश आयी, उस दिन मैं अपने एक मित्र सांसद के यहां बैठा था। देखा, सभी लोग खुश हैं, लेकिन मित्र उदास थे। कारण पूछा, तो उन्होंने कहा—यार दशकों के बाद एक मौका मिला था, लेकिन इस बरसात ने सब चौपट कर दिया।"

—अशोक रजनीकर

बिहार भवन
BIHAR BHAWAN

दिल्ली स्थित राज्यों के भवन मात्र खास लोगों के टिकने की ही जगह नहीं, उठापटक की राजनीति के अड्डे भी हैं। इन भवनों का क्या उपयोग होता है, इसका अंदाजा बिहार भवन की गतिविधियों से आसानी से लगाया जा सकता है। प्रस्तुत है, किस्सा-ए-बिहार भवन :

किस्सा बिहार भवन का

बिहार के एक सांसद थे विपिन बिहारी वर्मा। गांधी के चंपारण आंदोलन के बाद की पीढ़ी के कांग्रेसी। जितने दिन सांसद रहे चंपारण का कोई भी आता, तो इन्ही के घर पर ठहरता था। अपने सरकारी आवास में इन्होंने कई कमरे तो सिर्फ मेहमानों के लिए रखे थे। मेहमानों की देखभाल के लिए एक पूर्णकालिक सहायक थे। ये सज्जन आज बिहार कांग्रेस के एक बड़े आदमी हैं और लंबे समय तक मंत्री रह चुके हैं। वर्मा जैसे लोग किन मूल्यों को लेकर जीते थे, इसका उदाहरण काकोरी कांड के लिए काला पानी की सजा काट रहे क्रांतिकारी कमलनाथ तिवारी की वापसी के समय सामने आया। वर्मा को लगा कि तिवारी का योगदान बड़ा है और उन्हें सांसद होना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी जगह तिवारी को चुनाव लड़ाया।

वर्मा वाली हालत ही बाबू जगजीवन राम की थी। आखिरी दिनों तक उनके बंगले में बिहार भर से आये लोगों के ठहरने का इंतजाम था। वैसे यह अलग बात थी कि आखिर में कोई बड़ा आदमी उनके या किसी भी और आदमी के यहां ठहरने नहीं जाता था। जगजीवन बाबू के अतिथि सत्कार के तो ढेर सारे किस्से अभी भी प्रचलित हैं।

पर शायद सबसे आगे थे राजेन्द्र बाबू। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तो शायद राष्ट्रपति भवन बिहारियों का 'डेरा' ही बन गया था। सभी बड़े लोग सिर्फ उनका दर्शन करने ही नहीं, वहां अड्डा जमाने भी जाते थे।

और ये तीन नाम तो बस गिनाने भर को हैं। उस जमाने के किसी भी बिहारी सांसद और मंत्री के यहां ऐसी ही भीड़ लगती थी। एक तो तब सादगी का जोर अधिक था। दूसरे लोगों के व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत घनिष्ठ थे और फिर आज जैसा खर्च भी नहीं था। अधिकांश सांसद गांव से चावल-दाल-चिवड़ा वगैरह मंगाते थे। यहां का वेतन सिर्फ सब्जी वगैरह का खर्च संभालता था। फिर आने वाले कई लोग भी चावल, घी वगैरह ला देते थे।

पर घी की जगह डालडा का जमाना आ गया और सरकारी लोगों तथा अधिकारियों की दिल्ली दौड़ बढ़ गयी।

उस समय सरकारी लोगों के ठहरने के लिए दिल्ली में चार जगहें थीं—हैदराबाद हाउस, कोटा हाउस, पटौदी हाउस और कंस्टीट्यूशन क्लब। इनमें से हैदराबाद हाउस तो सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए था।

दरभंगा हाउस को केंद्र सरकार ने नहीं छोड़ा और उसे गुप्तचर पुलिस का केंद्र बना दिया। पर उसे भी लगने लगा कि दिल्ली में हर राज्य का कोई ऐसा ठिकाना होना चाहिए, जहां वहां से आये लोग ठहरें और जो उस राज्य का अपना हो। १९५७ से १९६० के बीच यह बात महसूस की गयी और तब केंद्र चाणक्यपुरी को विदेशी दूतावासों के लिए विकसित कर रहा था।

नया डेरा : उसने राज्यों को भी इसी इलाके में जमीन देने का फैसला किया। असम, म०प्र०, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, उ०प्र० के साथ ही बिहार ने यहां जमीन लेकर अपना पांच मंजिला 'बिहार भवन' बनाया। उसके बाद से यह दिल्ली आने वाले बिहारियों का 'डेरा' बना। ६० के दशक तक कांग्रेसियों के आपसी रिश्ते भी सत्ता की लड़ाई के कारण कटु हो चुके थे और अब किसी के घर ठहरने का रिवाज जाता रहा था।

१९७१ में इंदिरा गांधी के आगमन के बाद से डालडा का ही नहीं रिफाइंड का युग शुरू हुआ। राजनीति अब एकदम भिन्न धरातल से शुरू हुई और जोड़-तोड़ तथा पैसे का जोर बढ़ा। ललित नारायण मिश्र का उदय सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक नये बदलाव की ओर इशारा करता है। बिहार भवन अब इस बात का गवाह बनने लगा कि किस तरह केंद्र में गोटी बिठाने से केदार पाण्डेय मुख्यमंत्री बने, हटे, गफूर साहब आये, गये और आखिर में ललित बाबू के अनुज डा० जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने।

अगर इंदिरा गांधी का आगमन राजनीति में ढेर सारे बदलावों का द्योतक था, तो डा० मिश्र का आना बिहार की राजनीति में 'दिल्ली दौड़' की परंपरा बढ़ने का। भले ही दिल्ली दौड़ के कारण एन०डी० तिवारी नयी दिल्ली तिवारी कहे जाते हों, पर 'डाक्टर साहब' ने भी दिल्ली दौड़ने में कम जूते नहीं घिसे। यह दौर राजनीति में संजय गांधी के उदय का भी था और बिहार से नौजवानों की दिल्ली

. स्थायी कब्जा : बिहार भवन कीसबसे ऊपरी मंजिल पर जमे लोग

दौड़ भी शुरू हुई। अगुवा थे तारिक अनवर, कुमुद रंजन झा। बताना न होगा कि सबका अड्डा बनता था बिहार भवन ही और यह बिहार सरकार का केंद्र बनने की जगह बिहार इंका का केंद्र हो गया था। आखिर कार उसी दौरे में इंका अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने भी तो कहा था, "इंदिरा इज इंडिया।"

दिल्ली-दौड़ और बढ़ी : खैर जनता पार्टी का राज आया। उस दौर में भी दिल्ली और मजबूत बनी और बिहार भवन में लगने वाले मेलों की संख्या बढ़ती गयी। बल्कि १९७७ के बाद तो दिल्ली आने वाले बिहारियों की संख्या एकाएक तूफानी रफ्तार से बढ़ी। ये सारे लोग सरकारी नहीं थे। यह प्रक्रिया १९८२ के एशियायी खेलों के समय तक तो तूफान का रूप ले चुकी थी।

जल्दी ही जनता पार्टी सरकार गिरने और इंका की वापसी ने कांग्रेसियों को देश-राज्य पर अपना राज होने का भाव तो दिया ही, सत्ता का जबरदस्त केन्द्रीयकरण भी हुआ। पहले भी केदार पाण्डेय बहुमत कम होने के कारण नहीं, बल्कि केंद्र की नाराजगी के कारण गये थे। गफूर वहीं के इशारे पर चुने गये और वहीं के इशारे पर हटे। जगन्नाथ मिश्र का आना-जाना और फिर आना वैसे ही हुआ। फिर राजीव गांधी (तब इंका महामंत्री) की नाराजगी से उनका जाना और चन्द्रशेखर सिंह का आना हुआ।

चन्द्रशेखर सिंह का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में पटना की जगह दिल्ली चले आने का प्रतीक था। उनके आते ही हर हफ्ते बिहारी विधायकों की टोलियां उनके विरोध और पक्ष में दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाती रहीं। हर बात का गवाह बिहार भवन रहा।

चार रुपए में कमरा, चार ही रुपए में भोजन मिलने से दिल्ली में रहना किसी के लिए बोझ नहीं रहता। साथ ही आने-जाने का मुफ्त पास होता ही है। अपना पास न हो, तो किसी परिचित विधायक का पास चल जाता है। कमरे में एअरकंडीशनर चलाना हो, तो तीन रुपए और दीजिए। मंत्रियों को तो यह भी खर्च नहीं देना पड़ता। गाड़ी लेकर टहलना हो, तो मात्र एक रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर वह उपलब्ध है।

और फिर जब १९८५ के विधानसभा चुनावों की बारी आयी, तो बिहार भवन में सबसे अधिक गरमागरमी हुई। अब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने का कार्य जिला कमेटियों और प्रांतीय कमेटियों की जगह दिल्ली में हुआ और बिहार की ३२४ विधानसभा सीटों में से हरेक के लिए कम-से-कम पांच-पांच उम्मीदवार और उनके २५-५० समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाला। बिहार भवन की फर्श, लान पर भी लोग भर गये तथा बाहर चाय-पान नाश्ते की दुकानें भी लग गयीं।

खराब छवि के नाम पर चन्द्रशेखर सिंह ने जगन्नाथ मिश्र के समर्थकों का पत्ता कटवा दिया, पर जब विधानसभा के नतीजे निकले, तो डा० मिश्र दावा करने लगे कि वे लोग ही बहुमत में हैं और वे केंद्र से थोपे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जोर आजमाइश के लिए दिल्ली की दौड़ हुई। जगन्नाथ मिश्र ने अपने दूर के रिश्ते के दामाद और सांसद गौरीशंकर राजहंस के सफदरजंग एंक्लेव स्थित मकान में अड्डा जमाया और चन्द्रशेखर सिंह ने बिहार भवन में।

इस शक्ति-परीक्षण में बिहार भवन हार गया। मिश्र के समर्थन से बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बन गये। तुरंत दोनों की खटर-पटर शुरू हुई और दुबे ने मिश्र से नफरत करने वाले राजीव गांधी का दामन थाम लिया और फिर बिहार भवन की चलती शुरू हो गयी। बोफोर्स प्रकरण में राजीव के कमजोर पड़ने के पहले तक उनका जाना तय लग रहा था, पर उसके बाद मजबूत लगने लगे। जब राजस्थान में हरिदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर को लाया गया, तो दुबेजी के जाने की फिर से चर्चा शुरू हो गयी और अंततः वह चले गये।

इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में गृह राज्यमंत्री रहे पी०वेंकट सुबैय्या को जब मंत्रिमंडल से हटाया गया, तो उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। खुद राजनीतिक आदमी रहे सुबैय्या ने बिहार में कम विवाद नहीं पैदा किये। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति से उनकी लड़ाई जगजाहिर है। अभी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मरी नहीं हैं। हर महीने वह अब भी एक-दो-बार नियमित रूप से बिहार भवन के अतिथि बनते ही हैं। उनका यहां अपना सूट रिजर्व रहता ही हैं।

कौड़ी के मोल पांच सितारा होटल वाली सुविधा उपलब्ध कराने वाले बिहार भवन में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गहमागहमी नहीं रहती। यह साल भर और करीब-करीब २४ घंटे रहती है। एकदम भोर में पटना जाने वाली फ्लाइट पकड़ने जाने वालों की फौज रोज ही रवाना होती है और देर रात नीलांचल एक्सप्रेस से भी कोई-न-कोई आ जाता है। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आये हों, तो फिर क्या कहना?

एक चमत्कारी अधिकारी : हर बड़े-छोटे, इंकाई-विपक्षी, सरकारी-गैरसरकारी आदमी की बात को 'जी, सर' कहकर सुनने और उस पर अमल करने-कराने वाले प्रशासनिक अधिकारी कारन राम यहां की जिंदगी के एक अभिन्न अंग हैं। करीब सोलह साल पहले टाइपिस्ट की नौकरी से काम शुरू करने वाले कारन राम से हर 'बड़ा' आदमी खुश रहता है और नतीजा सामने है कि आज वह उपायुक्त के दर्जे में पहुंच गये हैं। इन बड़े लोगों को अपने को खुश रखने वाले आदमी को एकाध तरक्की दे देने में क्या जाता है।

कारन राम हैं भी चमत्कारी। ऐसा माना जाता है कि किसी मंत्रीजी के बेटे को कर्नाटक के मेडिकल-इंजीनियरिंग कालेज में 'मुख्यमंत्री कोटे' से एडमिशन दिलवाना हो या किसी अपने को रेलवे में आरक्षण, यह सब उनके बायें हाथ का खेल है। वह तुरंत किसी को भी बिहार भवन के पैड पर 'राज्यपाल के सहायक' और 'इनका पटना पहुंचना बहुत जरूरी' का सर्टिफिकेट देकर आरक्षण दिलवा सकते हैं।

कारन राम के रहते बिहार भवन में किसी रेजिडेंट कमिश्नर की भी नहीं चली। वर्तमान कमिश्नर वैद्यनाथ साहब तो नाराज रहते हुए रिटायर हो रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह हर बात में कारन राम द्वारा अपना फैसला लेना माना जाता है। आरोप लगाया जाता है कि ड्राइवरों की नियुक्ति के पूरे पैनल को दरकिनार करके उन्होंने मनमाने ढंग से अपने लोगों को इस काम में लगाया और इस सबमें कुछ चीजें तो इतनी गड़बड़ हो गयीं कि कहा नहीं जा सकता। इसी तरह एक बाहरी ड्राइवर को बिहार भवन की एक गाड़ी चलाने के लिए दी गयी और वह कार हवाई अड्डे से चोरी चली गयी। आज तक उसका पता नहीं है, पर ड्राइवर की नियुक्ति हो गयी। इसी तरह एक कार दिल्ली प्रशासन के खैबर पास स्थित बाड़े में कब से घिरी पड़ी है और उसे छुड़ा लाने की फुरसत किसी को नहीं है।

बिहार भवन के कर्मचारी बताते हैं कि कारन राम तभी अधिक सक्रिय होते हैं, जब कोई बड़ा आदमी आता है। उसके बाद वह कहां होते हैं, क्या करते हैं, इसकी खबर किसी को नहीं है। खुद आयुक्त साहब को पता नहीं होता कि वह कहां हैं? वैसे कारन राम ने दो काम और किये हैं। बिहार के

जीवन के रंग अजीब...

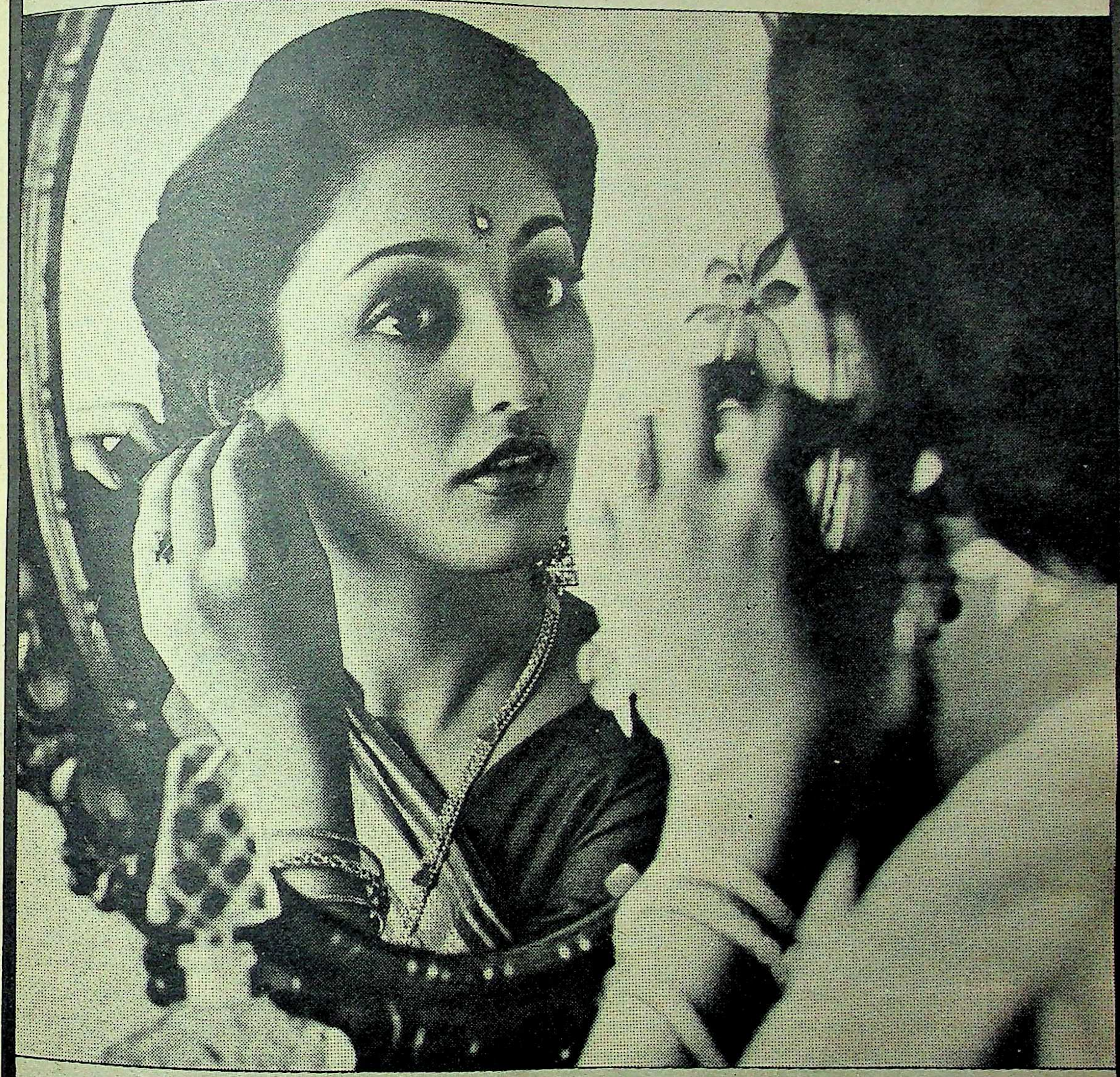

शुक्र है बोरोलीन करीब

खुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

BOROLINE
REGD. TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

सुखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

GD

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

Response 1035

जातिवाद का रोग यहां भी भर दिया है। जिस-तिस मंत्री का 'कैंडिडेट' बताकर अपने लोगों को नौकरी पर भरने का। वैसे यहां के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि कारन राम ने दिल्ली के उत्तम नगर और बिहार के अपने गांव (गया जिले के मसौढ़ी) में काफी जमीन खरीदी है, पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

बिहार भवन के लोग एक अन्य अधिकारी का नाम आते ही रोना शुरू करते हैं और ये सज्जन हैं बिहार भवन के इंजीनियर एस०पी० सिन्हा। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव के रिश्तेदार सिन्हा साहब भी कारन राम की तरह यहां लंबे अरसे से हैं। आर्थिक रूप से उन्होंने काफी तरक्की भी की है। बिहार सूचना केंद्र के एक अधिकारी का कहना है कि बिहार के लिए एक दूसरा भवन बनाने की जमीन मिली थी, पर वहां काम आगे नहीं बढ़ रहा है। कारण इंजीनियर साहब को ही बताया जाता है।

बिहार सूचना केंद्र के मुख्य अधिकारी मुक्ति नाथ उपाध्याय भी विवादों से बाहर नहीं हैं। दुबेजी के मुख्यमंत्री बनते ही जाने कहां से उनसे रिश्ता ढूंढ़कर उनके पास पहुंचे उपाध्यायजी मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बन बैठे और पहले के फूफा या मौसा वाले रिश्ते को भुलाकर दुबेजी को 'बाबूजी' कहने लगे। पर इनकी दुबेजी से भी अधिक उनके दामाद डा० रमेश पाण्डेय से छनती है और जिस बल पर बिहार को दो साल में औद्योगिक रूप से विकसित करने का दावा दुबेजी करते हैं उसकी खिचड़ी बिहार भवन में बैठकर यही लोग पकाते थे। बाहरी उद्योगपतियों को बिहार आने का न्यौता कैसे और किन शर्तों पर दिया जा रहा है, यह दिलचस्प है।

वैसे जब से बिहार में बाढ़ आयी है, डा० रमेश पाण्डेय का दिल्ली आना कम हो गया है। वह बिना एक पाई सरकारी सहायता लिये बिहार भर में राहत कार्य चलाने, फिर मुख्यमंत्री के बंगले के आगे कुटिया बनाने और अब अखबार निकालने जैसे कामों में व्यस्त रहने लगे हैं। वरना पहले बिहार भवन उनका एक स्थायी डेरा होता था और वह किसी अन्य कमरे में रहने की जगह मुख्यमंत्री सूट में ही टिकते थे। बिहार भवन के लोग भी जानते थे कि असली ताकत कहां है, सो उनकी हर तरह की खातिरदारी की जाती थी।

मुख्यमंत्री सूट की बात आयी, तो यह भी बता देना उपयुक्त लगता है कि जब भी मुख्यमंत्री बदलता है, इस कमरे का हर कुछ बदल जाता है। हर बार यह कमरा नये सिरे से सजाया जाता है।

दिल्ली ही क्यों ? : बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं—वे दो बातों से बहुत परेशान रहते हैं। एक तो पढ़ने आने और दूसरे इलाज कराने आने वालों की भीड़ से। हर आदमी मानेगा कि बिहार में आज इन दोनों चीजों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है और अन्य लोगों की कौन कहे, सरकार के कर्ताधर्ता लोग वहां की स्थिति सुधारने की जगह दिल्ली आकर इलाज कराना बेहतर समझते हैं।

> **कौड़ी के मोल पांच सितारा होटल वाली सुविधा उपलब्ध कराने वाले बिहार भवन में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गहमागहमी नहीं रहती। यह साल भर और करीब-करीब २४ घंटे रहती है। एकदम भोर में पटना जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वालों की फौज रोज ही रवाना होती है और देर रात नीलांचल एक्सप्रेस से भी कोई-न-कोई आ जाता है। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आये हों, तो फिर क्या कहना ?**

खुद मुख्यमंत्री दुबे इस मामले में आगे रहे हैं। नाती के इलाज की कौन कहे, अपना साधारण आपरेशन कराने के लिए भी वह दिल्ली ही आये और उनका जैसा राजसी इलाज हुआ, उससे बड़े-बड़े राजा महाराजाओं को ईर्ष्या होने लगे। जुलाई १९८६ में जब उनका आपरेशन हुआ, तो उसके तुरंत बाद मन्त्रिमंडल का विस्तार किये जाने की संभावना थी। इसलिए उन्हें देखने आने वालों की पूरी फौज उमड़ पड़ी। अधिकांश विधायक और जिले के कांग्रेसी नेता भी आ गये। माना गया कि जो दिल्ली नहीं जायेगा, वह दुबे विरोधी है, सो अधिकारियों की जमात भी दिल्ली पहुंच गयी।

विभिन्न राज्यों के भवन आपस में आवास की सुविधा का आदान-प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था काफी सस्ती पड़ती है। इस बिहार भवन के कर्ताधर्ता खासतौर से कारन राम कभी भी इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। कौन आया है, उसे सरकारी सुविधा मिलनी भी है या नहीं, इसकी परवाह किये बिना तुरंत पास के पांच सितारा होटल सम्राट में कमरे बुक करा लिये जाते हैं और सारा खर्च बिहार भवन के मत्थे। दुबेजी के इलाज के समय तो सम्राट के १६ कमरों के साथ ही लोदी होटल और जनपथ होटल में भी लोगों को ठहराया गया था। उस समय तो अर्दली तक को एक टिफिन ले जाने के लिए पूरी टैक्सी मिल जाती थी।

एक ओर रोज ऐसे कमरे लेने की जरूरत पड़ती है और दूसरी ओर कुछ लोग बिहार भवन में जमे पड़े रहते हैं। बिहार के एक प्रभावशाली इंका नेता राम लखन सिंह यादव के विवादास्पद सांसद पुत्र प्रकाश चंद्र तो 'गफूर चाचा' से बंगला पाने की उम्मीद में यहां के ३०८ नंबर कमरे में कई महीने तक डेरा जमाये रहे। उनको लगता था कि फ्लैट में जाना अपमानजनक है और फिर गफूर चाचा आवास मंत्री हैं, किस दिन के लिए!

इसी प्रकार के विधायक अवधेश सिंह अपने पिता का इलाज कराने के लिए १०१ नंबर कमरे में जमे रहे। शुरू में तो उन्होंने बिहार भवन की गाड़ी इस्तेमाल की, पर बाद में बिहार से अपनी गाड़ी मंगा ली। वैसे गया के कलेक्टर ने भी यहां काफी हंगामा किया था। यहा की एक गाड़ी के ड्राइवर को मंगा कर वह जाने कहां-कहां टहलाते रहे और कुछ हुआ नहीं! खुद आयुक्त ने हंगामा किया, पर गया के कारन बाबू का ही प्रभाव अधिक बड़ा साबित हुआ।

हां, एक बर्खास्त कमिश्नर विश्राम प्रसाद भी यहां के २०८ नंबर कमरे में डेरा जमाये हुए हैं। उन्हें यहां रहते साल भर हो गया है। वह अपना भोजन भी कमरे में ही पकाते हैं।

सिर्फ इलाज ही नहीं शिक्षा के मामले में भी बिहार के कर्ताधर्ता लोगों ने वहां की पूरी लगाम ढील दी है और अपने बाल-बच्चों को दिल्ली में पढ़ाते हैं। इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा शायद सबसे आगे हैं। उनके दोनों बेटों ने दिल्ली में पढ़ाई की और एक की शादी तो उन्होंने न गांव, न पटना और न ही दिल्ली में की, शादी हुई शिमला में और सारी जमात आते-जाते बिहार भवन में रुकी।

वैसे बिहार के मंत्रियों में नंबर दो माने जाने वाले रामाश्रय प्रसाद सिंह बिहार भवन को कोई कष्ट नहीं देते। उनके अपने सिचाई विभाग का गेस्ट हाउस साकेत में है ही। हाल में उनके किसी रिश्तेदार के इलाज के सिलसिले में यह गेस्ट हाउस कई महीने परेशान रहा। इस सबकी जांच गुप्तचर पुलिस ने भी की है, पता नहीं उसकी रिपोर्ट पर कुछ होता है या नहीं।

गुप्तचरी की बात आयी, तो एक तिवारीजी का नाम बिहार भवन का हर आदमी लेता है। बिहार पुलिस में सब-इंसपेक्टर दर्जे का काम करने वाले तिवारीजी बिहार भवन के लिए वी०आई०पी० हैं और महीने में कम-से-कम आधा समय यहीं गुजारते हैं। वह रहते भी हैं मुख्यमंत्री सूट के ठीक पास के दो नंबर कमरे में। इनका काम होता है अन्य प्रमुख लोगों के कामकाज पर नजर रखना और बताना नहीं होगा कि उनके शिकार की सूची में डा० जगन्नाथ मिश्र और रामाश्रय प्रसाद सिंह सबसे ऊपर हैं। डा० मिश्र जब भी दिल्ली में होते हैं, तिवारीजी के दर्शन जरूर हो जाते हैं।

बिहार भवन में इतना ही नहीं होता। कुछ खास और गड़बड़ चीजें भी होती हैं। वेस्टर्न कोर्ट में कुमुद रंजन झा को लेकर जिस तरह का हंगामा मचा था, उससे अधिक ही बड़ा हंगामा बिहार भवन में १९८४ की गर्मियों में १०४ नंबर कमरे में मचा। और वहां मौजूद मंत्रीजी ने बाद में संबोधित कर्मचारियों (जिनमें एक का नाम शैलेन्द्र है) से माफी भी मांगी।

बिहार भवन पुराण इतना भर ही नहीं है। सत्ता का केंद्रीयकरण बनने से इसकी महत्ता और बढ़ेगी ही। और फिर ऐसे सस्ते आरामगाह में कौन न दो-चार दिन रुकना चाहेगा।

—रामेश्वर तिवारी और अन्य

र कमरे में
की गाड़ी
नी गाड़ी
हां काफी
ाइवर को
और कुछ
पर गया
साबित

प्रसाद भी
हैं। उन्हें
ा भोजन

ले में भी
री लगाम
दिल्ली में
ी लोकेश
ों बेटों ने
उन्होंने न
शादी हुई.
ते बिहार

माने जाने
को कोई
का गेस्ट
के किसी
स्ट हाउस
गुप्तचर
ई पर कुछ

निवारीजी
लेता है।
ाम करने
के लिए
कम आधा
मंत्री सूट
ाम होता
र रखना
ी सूची में
सह सबसे
होते हैं,

ता। कुछ
टर्न कोर्ट
ा हंगामा
ार भवन
में मचा।
संबोधित
द्र है) से

नहीं है।
ता और
नगाह में

ौर अन्य

जीवन की मिठास के संग
संतूर का जम जाएगा रंग!
Santoor
Meetha Pan Masala
संतूर
मीठा पान मसाला

संतूर पेश करते हैं मन जीत लेने वाला मीठा स्वाद. अनूठा पान मसाला जो देशभर का प्रिय बन चुका है.
चाहें पाउच में से लीजिए या फिर डिब्बे में से ले लीजिए.
और घरभर की जुबान पर बार-बार इसी का नाम सुन लीजिए.

संतूर
मीठा पान मसाला

Govan/SMPM/1/88/HN

चुरहट लाटरी घोटाला

भाग्य निर्माताओं का भाग्य अधर में

अर्जुन सिंह के पुनः मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश लौटने पर चुरहट लाटरी के मामले को पुनर्जीवित करने की जो कोशिशें हो रही थीं, उनके और तेज हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। निरंतर नये- नये मोड़ लेते जा रहे मामले का सुधीर सक्सेना द्वारा पुनरावलोकन :

नये सिरे से हमले की आशंका : मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह

तीन साल से अधिक पुराना होने के बावजूद 'चुरहट लाटरी कांड' ने फिर तूल पकड़ लिया है। मामले के विधानसभा और फिर राज्यसभा में उठने के बाद एकबारगी लगा था कि कुछ ही दिनों में लोगबाग इस मामले को भूल जायेंगे, लेकिन इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटीं जिनसे यह प्रसंग पुनर्जीवित हो उठा। कुछ लोगों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने से मामला हाशिये में जाने से तो बच ही गया। मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह के सगे-संबंधियों की परेशानियां बढ़ भी गयी हैं। समूचे घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता कैलाश जोशी की याचिका के जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल हो जाने से भी महत्वपूर्ण मोड़ आया। फरवरी के पहले पखवाड़े में जब अर्जुन सिंह का जबलपुर के दौरे का कार्यक्रम बना, तो भाजपा सूत्रों ने दावा किया कि सिंह साहब दौरे के बहाने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विधिवेत्ताओं से सलाह-मशविरा करने जा रहे हैं।

पृष्ठभूमि : चुरहट लाटरी की कथा सीधे-सीधे चुरहट चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी से जुड़ी है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत इसका पंजीयन (क्रमांक १०९१७) १९ जनवरी '८२ को हुआ था। रीवा के सांसद मार्तण्ड सिंह सोसायटी के अध्यक्ष और अर्जुन सिंह के पुत्र और इंका विधायक अजय सिंह उर्फ राहुल इसके सचिव हैं। कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों में डा० सज्जन सिंह (शिवकुटी, सिविल लाइंस, रीवा), अर्जुन सिंह के बड़े भाई भुवनेश्वर प्रसाद सिंह (सिंगरौली हाउस, रीवा), अर्जुन सिंह के दामाद एस०पी० सिंह (नन्दन हाउस, रीवा) निकट संबंधी हैं। सोसायटी की सामान्य सभा के सदस्यों में जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा, सांसद मोतीलाल सिंह और इंद्रजीत पटेल शामिल हैं। जाहिर है कि सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों में मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों और समर्थकों का वर्चस्व है। यह भी स्पष्ट है कि सोसायटी से साधन-संपन्न और प्रभावशाली लोग संबद्ध है। इसी सोसायटी ने अपने गठन के अगले साल धन-संग्रह करने के लिए मध्यप्रदेश शासन से लाटरी व रैफल संचालन की अनुमति मांगी। इसके लिए अध्यक्ष मार्तण्ड सिंह के हस्ताक्षर से एक आवेदन वित्त-विभाग को भेजा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अर्जुन सिंह उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रदेश की राजनीति और प्रशासनतंत्र को अपने कूट-कौशल से मनचाहे तरीके से साध चुके थे। बहरहाल, तत्कालीन वित्त सचिव एम०आर० शिवरमन ने पत्र क्रमांक २५६०/चार/ आर-३/४३ दिनांक १६ दिसबर '८३ और तार क्रमांक २५६३/७१०४/आर०-३ दिनांक १७ दिसंबर '८३ से कलेक्टर, सीधी को सूचित किया कि सोसायटी द्वारा धन-संग्रह करने हेतु लाटरी या रैफल के संचालन के बाबत शासन को आपत्ति नहीं है, अतएव सोसायटी द्वारा इस बाबत आवेदन देने पर मध्यप्रदेश लाटरी (नियंत्रण तथा कर) अधिनियम १९७३ की धारा ७ के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाये। इस पर सोसायटी के सचिव अजय सिंह ने २९ दिसंबर '८३ को निर्धारित पत्रक में लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र कलेक्टर, सीधी को २ जनवरी '८४ को प्रस्तुत किया। इस अर्जी की तुरंत सुनवाई हुई और सीधी के तत्कालीन जिलाधीश अजय दास ने अगले ही दिन यानी ३ जनवरी को लाइसेंस जारी कर दिया। इस लाइसेंस में ड्रा की तारीख अंकित न करके 'एक वर्ष के भीतर लाटरी आयोजन करने' का उल्लेख किया और प्रयोजन में 'रेंजिग फंड्स फार ह्यूमैनीटेरियन परपज' लिखा गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रा की संख्या और दिनांक अंकित न करने की त्रुटि की ओर वित्त विभाग का ध्यान जल्द ही चला गया। इसकी पुष्टि इससे होती है कि विभाग के अवर सचिव ने ९ अक्तूबर '८४ को कलेक्टर, सीधी को अपने पत्र दिल्ली को बोर्ड के १८ जूलाई के पत्र और १० अक्तूबर के तार के उत्तर में लिखा कि सोसायटी ने अभी तक कोई भी 'रिटर्न आफ इनकम' प्रस्तुत नहीं किया है। इसी पत्र में उल्लेख है कि सोसायटी ने सर्वप्रथम ३१ मई '८२ को समाप्त काल में २६ हजार रुपए के दान और २२ हजार रुपए के मुद्रण व्यय की रसीदें प्रस्तुत की थीं। इसके बाद जून '८२ से मई '८३ के दरम्यान यूनियन कार्बाइड से डेढ़ लाख रुपए के दान-प्राप्ति और भवन-निर्माण पर करीब ६० हजार रुपए के व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत क्रमांक १९१५ में लिखा कि वित्त विभाग ने १६ दिसंबर '८३ को अपने पत्र में सोसायटी को एक ही ड्रा के लिए अनुमति दी थी, अतः वह (कलेक्टर,

सीधी) सोसायटी द्वारा आयोजित ड्रा, एकत्र धनराशि और पुरस्कार विजेताओं की सूची आदि की जानकारी विभाग को भेजें। चूंकि, कलेक्टर-कार्यालय में इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी (या सोसायटी द्वारा भेजी नहीं गयी), लिहाजा कलेक्टर ने सचिव अजय सिंह को १३ नवंबर '८४ को पंजीकृत क्रमांक ८०९/आर०डी०एम १९८४ भेजकर सूचित किया कि तीन जनवरी को प्रदत्त लाइसेंस केवल एक ही ड्रा के लिए है, इसलिए वह आगामी कोई भी ड्रा बिना नये लाइसेंस के या अनुमति प्राप्त किये आयोजित न करें, क्योंकि ऐसे में सभी आगामी ड्रा अवैध माने जायेंगे।

उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि ३ जनवरी '८४ तक तीन ड्राओं का आयोजन किया जा चुका था तथा इस पत्र के बाद सात मिनी ड्रा समेत कुल नौ और ड्रा निकाले गये। सोसायटी ने दिसंबर '८४ और जनवरी '८५ में क्रमशः तीन-तीन मिनी ड्रा निकाले और तदुपरांत दो मुख्य ड्रा ७ फरवरी और ७ अप्रैल को निकाले। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसायटी ने कुल १४.१९ करोड़ रुपए मूल्य के टिकट छापे और इनमें से ५ करोड़ ४४ लाख ४० हजार ५९० रुपए मूल्य के टिकटों की बिक्री हुई। शेष टिकट अनबिके रहे। संचालनालय अल्पबचत एवं राज्य लाटरी द्वारा वित्त सचिव को भेजे एक पत्र में उक्त आंकड़ों के उल्लेख के साथ कहा गया है कि ये सोसायटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आर०एन० गुप्ता द्वारा दिये गये हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सोसायटी की लाटरी से धन-संग्रह की युक्ति सफल रही।

शिकायतें: मद्रास सिटी पुलिस में हेड कांस्टेबिल महालिंगम ने शिकायत की कि उन्हें यह पुरस्कार टिकट क्रमांक सी०ई० ३१९२४७५ पर मिला, जिसे उन्होंने कोआपरेटिव बैंक, मद्रास की मार्फत चुरहट चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी, चुरहट, जिला सीधी को इनाम की राशि एकत्र करने के लिए भेजा। किंतु बैंक ने करीब एक माह बाद उन्हें टिकट यह कह कर लौटा दिया कि दिये गये पते पर सोसायटी का अस्तित्व नहीं है। हताश महालिंगम ने जब मद्रास के लाटरी एजेंटों से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें सोसायटी का पता मदुरै के लाटरी टिकट विक्रेता विमल एजेंसी से मिल सकता है। महालिंगम ने एजेंसी से संपर्क साध कर कहे अनुसार रीवा टिकट भेजा, लेकिन वह वहां से भी वापस आ गया। शिकायत मिलने पर जब लाटरी संचालनालय ने सोसायटी के सचिव अजय सिंह से जानकारी मांगी, तो उन्होंने सूचना दी कि टिकट के पीछे छपी शर्तों के अनुसार टिकट ड्रा के ४५ दिनों के भीतर न भेजकर २२५ दिनों के बाद उनके सेल्स आर्गेनाइजर मैसर्स ए० ऐंड ए० इंटरप्राइजेस, नयी दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि सोसायटी के मेमोरंडम आफ आर्टिकिल्स में लिखा गया है कि सोसायटी का मुख्यालय चुरहट में रहेगा, किंतु पत्र व्यवहार में मुख्यालय रीवा में होना बताया गया है। बहरहाल, विजेता टिकट पर पुरस्कार न देने पर यत्र-तत्र काफी होहल्ला हुआ

अजय सिंह

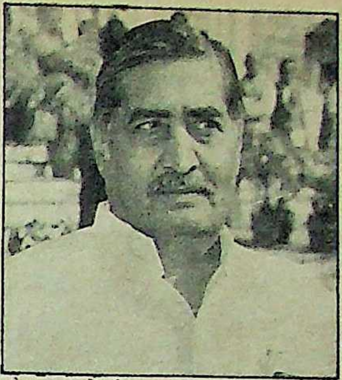
कैलाश जोशी

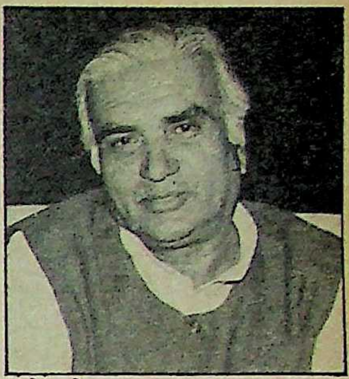
सुरेश सेठ

और बाद में महालिंगम को पुरस्कार राशि का भुगतान कर दिया गया।

नारायण चौक, छपरा निवासी बलदेव नारायण दुबे ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शिकायत भेजी कि टिकट क्रमांक सी०डी० १७५३१९२ पर उनकी लाटरी निकली है, किंतु सोसायटी से बारंबार पत्राचार करने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है। इस शिकायत की प्रति जब अजय सिंह को भेजी गयी; तो उन्होंने उत्तर दिया कि उक्त टिकट पर कोई इनाम नहीं निकला है। सोसायटी की चुरहट लाटरी के नाम से चर्चित लाटरी को लेकर महालिंगम और बलदेव नारायण दुबे के बाद तीसरी शिकायत दर्ज करायी बागी कांग्रेसी विधायक सुरेश सेठ ने। सुरेश सेठ ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा, "लाटरी के माध्यम से प्रदेश की जनता को धोखा दिया जा रहा है। लाटरी पर जगद्गुरु का फोटो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का फोटो तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फोटो छापकर लाटरी बेचना गैरकानूनी है। करोड़ों के घपले इन लाटरियों के माध्यम से प्रदेश में हो रहे हैं।

उक्त लाटरी को लेकर लाटरी संचालनालय को कुछ और भी शिकायतें मिलीं, जिन्हें संचालनालय ने पत्र क्रमांक क्यू/संराला/ईशू/८६ दिनांक ३१ मार्च '८६ को वित्त विभाग को भेज दिया। मगर तथ्यों से ऐसा नहीं लगता कि तत्कालीन वित्त सचिव ने शिकायतों को गंभीरता से लिया या कोई कार्रवाई की। यह आज भी विवाद का मुद्दा है कि लाटरी से सोसायटी को पुरस्कार बांटने के बाद कुल कितनी आय हुई? लाटरी संचालनालय के सूत्रों के अनुसार यह बात स्वयं अजय सिंह ने स्वीकार की कि उनके विक्रय एजेंट ए० ऐंड ए० इंटरप्राइजेस, नयी दिल्ली के दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे में विभाग ने कतिपय पुरस्कार विजेता टिकट भी जब्त कर लिये थे। परिणामतः उन टिकटों पर घोषित इनामों का वितरण नहीं किया जा सका। इन्हीं दिनों सोसायटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आर०एन० गुप्ता ने संचालनालय को सूचना दी कि ३१ जुलाई '८६ तक सोसायटी को ९८ लाख ६२ हजार रु० की राशि प्राप्त हो चुकी थी।

चुरहट लाटरी में घोटाले को लेकर विवाद दिनोदिन गहराता गया। बाद की कुछ घटनाओं ने विवाद की आग में घी का काम किया। ऐसी ही एक घटना एक आयकर अधिकारी के तबादले के रूप में हुई।

विवाद: चुरहट लाटरी में घोटाले को लेकर विवाद दिनो-दिन गहराता गया। बाद की कुछ घटनाओं ने विवाद की आग में घी का काम किया। ऐसी ही एक घटना एक आयकर अधिकारी के तबादले के रूप में हुई। रीवा में पदस्थ आयकर अधिकारी सी०पी० मिश्रा ने जून में रीवा से जबलपुर किये गये तबादले के विरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, जबलपुर में याचिका दाखिल की कि उनका स्थानांतरण अवैध, दुर्भावनापूर्ण और आयकर के विभाग के तबादलों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। उक्त आयकर अधिकारी ने सोसाइटी के कार्यालय पर डाले गये छापे में जब्त कागजात के आधार पर सोसायटी के विरुद्ध १ करोड़ ७० लाख २८ हजार ३०० रुपए के अतिरिक्त आयकर का आदेश जारी किया था। मिश्र ने अपने छह माह के कार्यकाल में रीवा सर्कल की आय १.९४ करोड़ रु० से बढ़ाकर २.६८ करोड़ रुपए कर दी थी। उनकी याचिका की सुनवायी न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष एस०के० चिब व सदस्य के०बी० खरे की पीठ ने की और तबादले के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी।

मध्यप्रदेश लाटरी नियंत्रण एवं कर अधिनियम १९७३ की धारा ७ के तहत लाइसेंस की स्थिति में नियमानुसार २५ प्रतिशत कर का प्रावधान है, हालांकि, लाटरी से आय विवादास्पद है, किंतु अगर अजय सिंह की सूचना को सही मान लिया जाये, तो भी सोसायटी पर करीब २५ लाख रुपए के कर का मामला बनता था। कार्यालय, आयकर आयुक्त, जबलपुर ने १९ अक्तूबर '८५ को सचिव, सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज, नयी

शिशु कल्याण केन्द्र
CHILDREN WELFARE SOCIETY
CHURHAT

किसका कल्याण ? :
शिशु कल्याण केंद्र

किया गया, लेकिन इसके बाद देखा गया कि सोसायटी ने लेखा-अवधि को बदल दिया और दिसंबर '८३ में समाप्त अवधि का नया आय-व्यय ब्यौरा तैयार किया। इस ब्यौरे में ३८१००० रुपयों से अधिक अनुदान का उल्लेख था। पत्र पर गौर करें, तो जाहिर होता है कि लेखा अवधि में फेरबदल का यह क्रम आगे भी जारी रहा, जिसके औचित्य पर आयुक्त ने प्रश्नचिह्न भी लगाया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया कि सोसायटी के संविधान में लाटरी निकालने या चलाने का कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है।

सोसायटी के चुरहट के पते पर भेजे गये टिकट के बैरंग वापस आने का जिक्र पहले हो चुका है। उक्त पत्र में सोसायटी की गतिविधियों से पदाधिकारियों की अनभिज्ञता का भी रोचक उल्लेख है। वर्णित प्रसंग के अनुसार, दिये गये पते पर उपलब्ध डा० सज्जन सिंह ने आय कर अधिकारी से कहा कि वह कोई भी सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं, अत: अधिकारी को भोपाल में सचिव अजय सिंह या एडवोकेट बी०एम० गुप्ता से संपर्क करना चाहिए। विभागीय दायित्व के निर्वाह के फेर में आय कर अधिकारी ने १७ अक्तूबर '८५ को अजय सिंह के रीवा प्रवास के दरम्यान उनसे भेंट की चेष्टा की, और-तो-और वह सत्तर किमी० दूर शिवराज नगर (चुरहट, सीधी) भी गये, किंतु उनकी भाग-दौड़ निरर्थक रही। इन सब बातों से यह तथ्य उजागर होता है कि सोसायटी का मुख्यालय सिर्फ नाम को ही चुरहट में स्थित था लेकिन सारी गतिविधियों का संचालन भोपाल से होता था। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि मध्यप्रदेश शासन ने सोसायटी को अनेक विवादों के बावजूद आय कर में छूट प्रदान कर दी। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाटरी में कथित घोटाले का मामला राज्यसभा में उठाने के बाद कई माह तक शांति रही, किंतु अनिरुद्ध शास्त्री ने सोसायटी के पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा कर मामले को फिर जनचर्चा का विषय बना दिया।

अदालत में : अनिरुद्ध शास्त्री की याचिका के साथ कुछ मजेदार बातें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सोसायटी के चारों पदाधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद पिछले साल दिसंबर में वकील बृजबिहारी दुबे के जरिये पुनरीक्षण याचिका दायर कर अर्जुन सिंह को अभियुक्त बनाने की याचना की, किंतु ५ जनवरी को उन्होंने वकील मनोहर दलाल के माध्यम से छठे सत्र न्यायाधीश शंभु सिंह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी ही पुनरीक्षण याचिका को निरस्त करने का अनुरोध किया। दलाल ने इंदौर के महेंद्र जैन के अर्जुन सिंह को अभियोजित करनेवाले उस आवेदन को प्रस्तुत किया, जिसे राज्यपाल ने नामंजूर कर दिया था। शास्त्री के पूर्व वकील दुबे ने पुनरीक्षण याचिका को निरस्त करने का विरोध किया, किंतु न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील विनीत गोधा की दलील सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही ११ जनवरी को सोसायटी के चार पदाधिकारियों व अर्जुन सिंह के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिसौदिया के समक्ष दाखिल हुआ। १४ जनवरी को पत्रकार रवींद्र दुबे इसमें हस्तक्षेपकर्ता की हैसियत से शरीक हो गये और उनके व वादी के वकील बने बृजबिहारी दुबे। वादी आर०डी० सक्सेना व रवींद्र दुबे ने कहा कि सोसायटी का गठन १६ जनवरी '८२ को अर्जुन सिंह के निवास में हुआ और सिंह ने पंजीयन में मदद की। चुरहट लाटरी के ३ करोड़ ६३ लाख रुपए के इनाम नहीं बांटे गये और यह राशि सोसायटी ने हड़प ली। दलील में कहा गया कि पदाधिकारियों ने धोखे से पैसे बटोरे हैं।

भोपाल की अदालत में ये मामले चल ही रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने पूर्व सांसद निर्मल चंद जैन के जरिये एक याचिका जबलपुर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। लाटरी अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्होंने दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने की मांग की। 'माया' से चर्चा में कैलाश जोशी ने कहा कि कर मुक्ति आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित या अनुशंसित नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वोरा के रवैये को गड़बड़ बताते हुए उन्होंने यह भी जानकारी दी कि २८ दिसंबर '८७ को काबीना की बैठक में 'प्रेसी' (संक्षेपिका) में टैक्स में छूट को 'रेक्टीफाई' करने की बात कही गयी थी, किंतु किसी कारणवश प्रेसी बैठक में रखी ही नहीं गयी। जोशी की भांति पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा भी मानते हैं कि सोसायटी ने घोटाला किया है और वोरा सरकार का रवैया अनुचित रहा है। पटवा ने कहा कि भाजपा इसे हर स्तर पर जोरशोर से उठायेगी।

'माया' से चर्चा में कतिपय विधि-विशेषज्ञों ने इस ओर भी संकेत किया कि चुरहट लाटरी को प्राइवेट या निजी लाटरी माना जाये या नहीं। यह विवादास्पद इसलिए है, क्योंकि लाटरी के टिकट सदस्यों को अथवा क्षेत्र विशेष में न बेचकर संपूर्ण भारतवर्ष में बेचे गये। बगैर अनुमति के लाटरी का दफ्तर एक से अधिक स्थानों पर रखना भी कानून-सम्मत नहीं है। टिकटों की बिक्री और पुरस्कारों के वितरण को लेकर विरोधाभासी बयान सामने आये हैं। बहरहाल, विधानसभा के भीतर और बाहर चर्चा के बाद अब यह मामला अदालत की परिधि में है। ■

सायटी ने
कारियों ने

ल ही रहे
र्व सांसद
जबलपुर
धिनियम
ने दोषी
ांग की।
कि कर
दित या
रवैये को
री दी कि
में 'प्रेसी'
ई' करने
वश प्रेसी
ांति पूर्व
हैं कि
सरकार
कहा कि
ठायेगी।
शेषज्ञों ने
टरी को
हीं। यह
के टिकट
र संपूर्ण
टरी का
कानून-
कारों के
मने आये
र बाहर
रिधि में

ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेन्ट केक
ज़बरदस्त झाग। किफ़ायती धुलाई।
किफ़ायती धुलाई
Contract KP-96-86 HIN

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा
डिटर्जेन्ट केक

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

सही आकार, रहे एकसार सालों साल, साल दर साल

साल दर साल, साल दर सा
ल, साल दर साल, साल दर
साल, स   साल, साल
दर स   साल, स

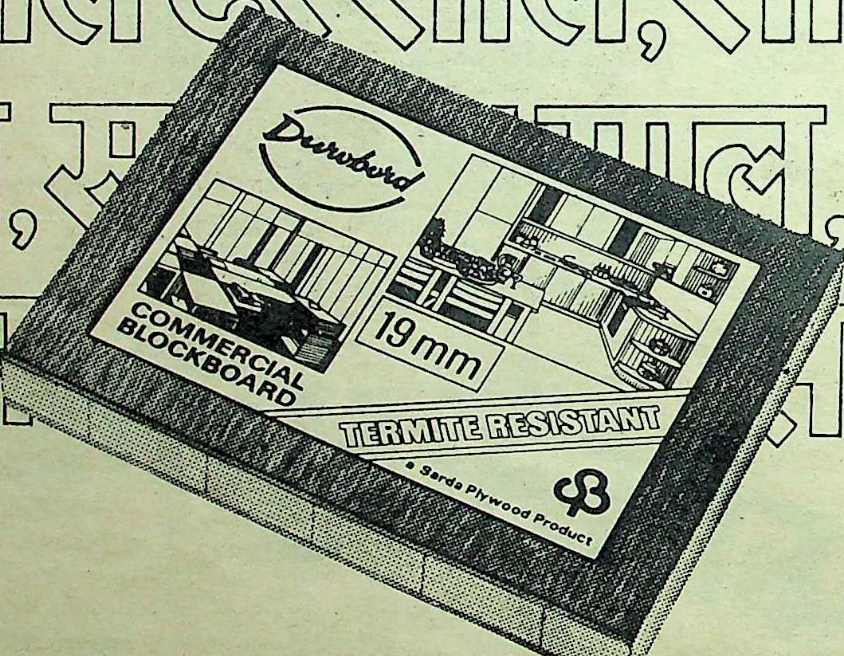
Durobord
COMMERCIAL BLOCKBOARD
19 mm
TERMITE RESISTANT
a Sarda Plywood Product

यह है ड्यूरो – ब्लॉकबोर्ड का हीरो

न फैलाव, न सिंकुड़न, न टेढ़ा होने की प्रवृत्ति । न ही फूलकर खपच्चियां उतरने की शिकायत । कार्यकुशलता में सबको पीछे छोड़कर, ड्यूरो सबसे आगे है । इसीलिए ड्यूरोबोर्ड ब्लॉकबोर्ड की दुनिया में सरताज है । और रहेगा—साल दर साल...

सारदा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
जैपुर (असम)
मुख्य विक्रय कार्यालय ९/१३, डी. बी. गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

DPS/SPI-878

दीवार फांद कर
सत्ता में : शिवचरण माथुर

शिवचरण माथुर

आते ही विरोध

दिल्ली की कृपा से शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बन गये हैं, लेकिन स्वागत के साथ ही विरोधियों ने उनकी विदाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या माथुर विपक्ष और इंका के असंतुष्टों के अभियान से अपना बचाव कर सकेंगे ?

मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवचरण माथुर को एक तरफ संयुक्त विपक्ष से जूझना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हीरालाल देवपुरा भी मोर्चा बनाने में लग गये हैं। श्री जोशी ने फिलवक्त तो मौन साध रखा है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में कब उनका धीरज टूट जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को कैबिनेट में शामिल किये जाने के बावजूद शपथ ग्रहण न करना, चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि वह उपमुख्यमंत्री का पद चाहते थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री माथुर इसके पक्ष में नहीं थे। उल्लेखनीय है कि श्री पहाड़िया प्रारम्भ में मंत्रिमंडल में शामिल न होने की वजह अपनी बीमारी बता रहे थे। बाद में जब आलाकमान ने सवाल किया, तो उन्होंने अपनी पत्नी सांसद श्रीमती शांति पहाड़िया की बीमारी की बात कही। अखबारों ने जब इसे भरतपुर में उठे आंदोलन के साथ जोड़ा, तो पहाड़िया स्वयं प्रधानमंत्री से मिले और अपनी वफादारी का वास्ता देते हुए दिल्ली में रहकर सेवा करने की इजाजत चाही। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने उनकी इस इच्छा को स्वीकृति दे दी है।

नया मंत्रिमंडल : श्री माथुर ने आलाकमान की स्वीकृति से अपने २१ सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन कर यह साबित कर दिया है कि वह प्रदेश कांग्रेस संगठन की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। मसलन, प्रदेश कांग्रेस संगठन ने श्री गहलोत के नेतृत्व में उन कांग्रेसियों को संगठन के ब्लाक से जिले स्तर तक अलग कर दिया था, जिन्हें सत्ताधारी दल ने बुरी छवि वाला करार देते हुए टिकट से वंचित किया था। हरिदेव जोशी ने इन तिरस्कृत लोगों से तालमेल बिठा कर अशोक गहलोत को सबक सिखाना चाहा था, पर इसका नतीजा विपरीत हुआ और इस हद तक हुआ कि श्री जोशी की मुहिम में सहयोग करने वाले सारे मंत्रियों को मंत्रिपद से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल श्री जोशी के मंत्रिमंडल में उपमंत्री रही श्रीमती बीना काक को तरक्की देकर राज्यमंत्री बनाने के फैसले को बड़े आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। हालांकि २१ सदस्यीय मंत्रिमंडल में ग्यारह लोग ऐसे शामिल किए गये हैं, जिनकी अटूट आस्था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गहलोत के प्रति रही है। पूर्व मंत्रिमंडल में इस दृष्टि से केवल रामकिशन वर्मा ऐसे मंत्री थे जिन्हें संगठन के प्रयासों से मंत्री-पद हासिल हुआ था।

वैसे श्री माथुर के साथ संकट की घड़ियों में उनके पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीराम गोटेवाला, दुल्हाराम व देवेन्द्र सिह रहे हैं। इन्हें आलाकमान ने बुरी छवि वाला करार देते हुए पिछले आम चुनाव में टिकट से वंचित कर दिया था, पर बदले हुए समीकरणों ने इन्हें निखरी छवि का बना दिया है। नये मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री माथुर ने विशेष रूप से अपना और श्री गहलोत का खयाल रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोशी की रणनीति से श्री माथुर का उदयपुर सम्भाग और श्री गहलोत का जोधपुर सम्भाग संकट भरा हो गया था। इससे मुक्ति के लिए श्री माथुर ने जोधपुर सम्भाग से सात मंत्री बनाये, जिनमें माधवसिह दीवान (सोजत), नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) व रघुनाथ बिश्नोई

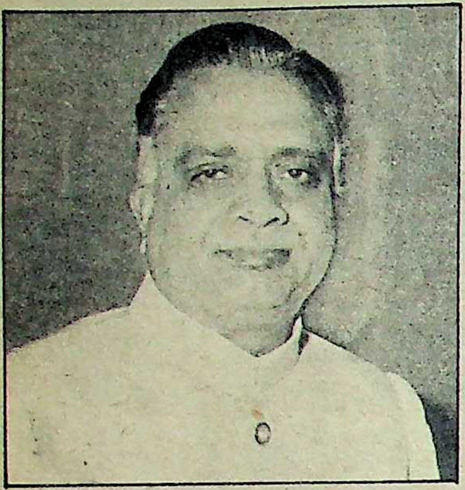

साक्षात्कार/शिवचरण माथुर

जोशीजी से मेरा सैद्धांतिक मतभेद रहा है

शिवचरण माथुर पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बदले हुए हैं। उनके कार्यालय में काम करने वाले निजी सचिव व अन्य कर्मचारी सबका व्यवहार इतना शिष्ट और विनम्र है कि 'माया' से साक्षात्कार का समय निश्चित कर वह एक सप्ताह टाल गये फिर भी बुरा नहीं लगा। मुख्यमंत्री की व्यस्तता का यह आलम है कि प्रातः सात बजे प्रारम्भ होने वाली उनकी सरकारी और संगठन की बैठकें देर रात तक चलती रहती हैं। दंभ और हठ के पर्याय रहे श्री माथुर अब विनम्रता की मूर्ति नजर आते हैं। समस्याओं और चुनौतियों से घिरे मुख्यमंत्री ने 'माया' से खुल कर बात की। प्रस्तुत हैं, उसी बातचीत के कुछ अंश :—

माया: जोशी सरकार पर आरोप रहा है कि वह संगठन को गौण कर अपने को प्रमुख मानती रही। आपका इस सन्दर्भ में क्या खयाल है?

माथुर: आरोप की बात तो मैं नहीं कहता, पर मैं यह मानता हूं कि संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन ही सरकार बनाता है। उसी के मेनिफेस्टो (घोषणा-पत्र) पर जीतकर हम लोग सांसद एवं विधायक बनते हैं। घोषित मेनिफेस्टो को क्रियान्वित करने की हम लोगों की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में संगठन और सरकार में तालमेल होना स्वाभाविक है।

माया: जोशीजी के प्रमुख सलाहकार कहे जाने वाले मोहन छंगाणी, राजा मानसिंह हत्याकांड को लेकर उठे आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय हैं? आपका क्या कहना है?

माथुर: वह सक्रिय हैं और बहुत से लोग भी सक्रिय हैं। उनका राजनीतिक उद्देश्य है। हालांकि इस मामले में है कुछ नहीं। सब जानते हैं कि राजा मानसिंह मेरे अच्छे मित्र थे। उनके मेरे घरेलू संबंध थे। कहीं कोई घटना हो जाती है, तो उसके लिए कोई मुख्यमंत्री कहां तक जिम्मेदार होता है, यह सोचने की बात है। पर यह लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक हो गये हैं। अब इसमें बहुत से लोग हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से क्या फायदा?

माया: आपके मुख्यमंत्री बनते ही जाति विशेष के नेताओं ने आपको मानसिंह हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए आन्दोलन रचा है। इस आन्दोलन को आप क्या कहेंगे?

माथुर: मैंने कहा न कि यह राजनीति से प्रेरित है।

माया: आपके मुख्यमंत्री बनते ही विपक्ष के नेताओं को भी उक्त हत्याकांड के लिए आप ज्यादा जिम्मेदार नजर आने लगे हैं। इसका क्या कारण है?

माथुर: इसके पीछे केवल एक राजनीति है। हम कुछ काम करना चाहते हैं और उससे हमारी इमेज जनता के बीच काम करने वालों की बनती है। इसे विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वह अपना काम कर रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

> जोशीजी की कार्य प्रणाली से मेरा सैद्धांतिक मतभेद रहा है। इस मतभेद को मैंने हमेशा अपनी पार्टी में व्यक्त किया है। मैं शुरू से मानता रहा हूं कि आवश्यकताओं को अगर विस्तार से समझा जाये, तो साधन भी उपलब्ध हो जायेंगे और उनका समाधान भी हो जायेगा। अब आने वाले समय में मैं साबित करूंगा कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है।

माया: पूर्व मुख्यमंत्री जोशी की योजनाओं और कार्यप्रणाली से आपने हमेशा नाइत्तफाकी दिखायी है। अब जब आप मुख्यमंत्री हैं, तो योजनाओं का स्वरूप क्या होगा? इन्हें लागू करने के लिए राजस्व कहां से प्राप्त करेंगे? सीमित साधनों से सूखे और पेयजल की समस्या का समाधान कैसे होगा?

माथुर: देखिये, जोशीजी की कार्य-प्रणाली से मेरा सैद्धांतिक मतभेद रहा है। इस मतभेद को मैंने हमेशा अपनी पार्टी में व्यक्त किया है। मैं शुरू से मानता रहा हूं कि आवश्यकताओं को अगर विस्तार से समझा जाये, तो साधन भी उपलब्ध हो जायेंगे और उनका समाधान भी हो जायेगा। अब, आने वाले समय में मैं साबित करूंगा कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। फिलवक्त इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकेगी। मुझे वक्त दीजिये, मैं साबित करूंगा।

माया: आपके पूर्व मुख्यमंत्रित्व काल में आप पर प्रशासन में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इस आरोप के संबंध में आपकी क्या टिप्पणी है?

माथुर: देखिये, मेरी जाति बहुत माइनारिटी (अल्प संख्या) में है। अब डाक्टर्स, इंजीनियर्स मेरी जाति में हैं, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कोइन्सिडेन्टली (संयोगवश) वे लोग सीनियर (वरिष्ठ) हैं। जोशीजी ने खुद अपना मुख्य सचिव एक माथुर (वी०बी०एल० माथुर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव पद पर हैं) को रखा। अब इसमें मेरा क्या दोष है?

माया: केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री नटवरसिंह आपके मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं बताये जाते, क्या यह सच है?

माथुर: मैं तो जानता नहीं कि वास्तविकता क्या है, पर अब किसी को नाराजगी होना नहीं चाहिए। मैं तो काम करने के लिए आया हूं। फिर अगर आज नाराजगी है, तो मेरा काम देख कर कल समाप्त हो जायेगी।

माया: अगर नाराजगी है, तो ऐसी स्थिति में श्रीमती दीपा द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन को क्या नटवरसिंह का समर्थन प्राप्त होना नहीं कहा जा सकता?

माथुर: यह मैं कुछ नहीं जानता हूं।

माया: आपके मंत्रिमंडल के गठन को देखकर एक आरोप लग सकता है कि आपने पुराने मंत्रियों को न लेकर अनुभव का अपमान किया है।

माथुर: मैंने पुरानों को भी लिया है और नयों को भी लिया है। फिर नयी सृजन शक्ति को लेना पुरानों का अपमान कैसे कहा जायेगा? इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। अब तक लोगों ने मेरे इस प्रयास की तारीफ की है।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/ श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

सब जानते हैं मेरे पिता को किसने मरवाया

भरतपुर जिले के डीग निर्वाचन क्षेत्र से अपने पिता की मृत्युं के बाद श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुईं। राजा मानसिंह की तथाकथित हत्या के बाद डीग निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती कौर के सामने कोई कांग्रेसी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। शिवचरण माथुर के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर श्रीमती कौर ने विरोध का आन्दोलन खड़ा कर दिया है। प्रस्तुत हैं, इस मुद्दे पर 'माया' के साथ हुई उनकी बातचीत के प्रमुख अंश:

माया: शिवचरण माथुर का पुनः मुख्यमंत्री बनना आपको कैसा लग रहा है?

कृष्णेन्द्र: मैं इस समाचार से स्तब्ध थी। उन सब लोगों के लिए यह एक बुरा समाचार था जो प्रजातन्त्र में आस्था रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को मेरे पिता की हत्या की साजिश में जिम्मेवार ठहरा कर पद से हटाया गया था, उसे पुनः मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया?

माया: वैसे तीन साल में हत्याकांड की सुनवाई कितनी आगे बढी है?

कृष्णेन्द्र: मैं १९८६ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिली थी। उसके परिणामस्वरूप अब विशेष अदालत में हर रोज सुनवाई हो रही है।

माया: जोशी सरकार से इस मामले में आपको कोई शिकायत रही।

कृष्णेन्द्र: उस वक्त भी पेपर्स मूव करते रहे। उसी का नतीजा है विशेष अदालत। देखिये, जोशीजी के जमाने में भी सब कुछ अपने आप नहीं हो गया। फिर विपक्ष की मदद हमेशा मिली है इसलिए सरकार टालना चाहकर भी टाल नहीं सकी।

माया: मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वह दिवंगत राजा साहब का बड़ा सम्मान करते थे?

कृष्णेन्द्र: फिर हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा क्यों दिया था? यह कहने के लिए तो पहले भी वक्त था, तब क्यों नहीं बोले? ड़ीग और भरतपुर का हर आदमी जानता है कि मेरे पिताजी की हत्या किसके इशारे पर हुई। आम जनता कहती है कि शिवचरण ने आर्डर दिया था कि मुझे राजा मानसिंह जिन्दा अथवा मुर्दा चाहिए।

माया: आप समझती हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक होकर सामने आयेगा?

कृष्णेन्द्र: क्यों नहीं होगा विपक्ष एक? प्रजातंत्र की रक्षा का दायित्व क्या कोई मेरी अपनी बात है। राजस्थान के लोग पिछले विधानसभा चुनावों में इसका जवाब दे चुके हैं और इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष के साथ-साथ जनमोर्चा के नेता भी इस मुद्दे पर राजस्थान में सक्रिय हो रहे हैं।

माया: केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री नटवरसिंह का इस मामले में क्या रुख है?

कृष्णेन्द्र: उन्हें भी पत्र लिखा है। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे ज्यादा तो आपको पता है।

—ओम सैनी

(सांचेर) को केबिनेट मंत्री और श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर), मांगीलाल आर्य (जालौर), राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) और सूरजपाल सिंह (भीनमाल) को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने अपने सहित छह लोग उदयपुर से लिये हैं, जिनमें केबिनेट मंत्री हनुमान प्रभाकर (मालवी), राज्यमंत्री श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा), कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर), लक्ष्मण सिंह (भीम) तथा उपमंत्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) शामिल हैं।

इस मंत्रिमंडल के गठन को देखकर यह भी स्थापित होता है कि प्रदेश की राजनीति में अब मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय गृहमंत्री बूटासिंह का दखल बन गया है। उसके संसदीय क्षेत्र जालौर जिले के चार इंका विधायकों में से तीन को मंत्री-पद दिया गया है। श्री माथुर ने श्री जोशी के चाणक्य, सांसद नवल किशोर को सबक सिखाने के लिए जयपुर जिले से चन्द्रशेखर शर्मा और भैरूलाल भारद्वाज को मंत्रिमंडल में लिया है। इसी तरंह बीकानेर सम्भाग से बुलाकीदास कल्ला को केबिनेट स्तर का मंत्री बनाकर जोशी समर्थक श्रीमती कांता खतूनिया के वर्चस्व पर हमला बोल दिया है।
समर्थक श्रीमती कांता खतूरिया के वर्चस्व पर हमला बोल दिया है।

राजस्थान की जातीय गठबंधन से चलने वाली राजनीति से निपटने के लिए श्री माथुर ने अपने मंत्रिमंडल में पांच ब्राह्मण, चार जाट, दो गुर्जर तथा चार अनुसूचित जाति व दो जनजाति के मंत्री नरेन्द्र सिंह और जयपुर के विधायक शिवराम शर्मा माथुर मंत्रिमंडल के विरुद्ध उपजे किसी भी असंतोष में शामिल होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गये हैं।

मानसिंह का भूत: श्री माथुर की वर्तमान व्यूह रचना को पहला मुकाबला मुख्यमंत्री पद संभालते ही राजा मानसिंह की हत्या के मामले को लेकर भरतपुर जिले में शुरू हुए आंदोलन से करना पड़ा है। बीस जनवरी को जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जाट रियासत के रूप में मशहूर रहे भरतपुर जिले के विभिन्न कस्बों में रोष प्रकट किया गया। २३ जनवरी को नियोजित रूप से भरतपुर शहर के कालेज और स्कूल बंद किये गये। लोकदल-अ के विधायक यदुनाथ सिंह और ब्रज प्रदेश संघर्ष समिति के लोगों ने सभाओं में घोषणा की कि जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे, आंदोलन जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि फरवरी १९८५ में विधानसभा चुनावों से पूर्व तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री माथुर का हेलीकाप्टर डीग के निर्दलीय विधायक जाट नेता राजा मानसिंह ने अपनी जीप से टक्कर मार कर तोड़ दिया था। फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए गयी पुलिस उनकी मृत्यु का कारण मुठभेड़ में गोली लगना बताती है, जबकि घटनाचक्र हत्या जैसे संकेत देते हैं। श्री माथुर को इस घटना के बाद मुख्यमंत्री-पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। बावजूद इसके लोकसभा की सभी सीटें जीतने वाली कांग्रेस-इ को दो सौ सदस्यों वाली विधानसभा में केवल ११५ सीटों से ही संतोष करने को मज़बूर होना पड़ा था।

भरतपुर जिले के इस आंदोलन को डीग क्षेत्र से निर्दलीय विधायक एवं दिवंगत राजा मानसिंह की बेटी श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने चला रखा है। २३ जनवरी को उन्होंने पत्रकारों के सामने घोषणा की कि हम पहले भरतपुर जिले का तहसील मुख्यालय बंद करेंगे और बाद में भरतपुर बंद करेंगे। श्रीमती दीपा ने जयपुर में विपक्ष के नेताओं का समर्थन हासिल कर आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाने की योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत २७ जनवरी को उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और राजभवन के बाहर धरना देते हुए एक दिन का अनशन किया। श्रीमती दीपा के साथ ज्ञापन देने वालों में विपक्ष एवं भाजपा के नेता भैरोंसिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष मित्र रहे निर्दलीय विधायक मोहन छंगाणी शामिल थे। श्री माथुर के खिलाफ विपक्ष का एक होना स्वाभाविक है। वहीं श्री जोशी के समर्थक छंगाणी का पहल करना, ऐसा संकेत समझा जा सकता है कि आगे चलकर राजस्थान कांग्रेस-इ विधायक दल इस मसले पर दो गुटों में विभाजित हो सकता है।

वैसे श्रीमती दीपा ने कार्यवाहक राज्यपाल श्री वर्मा को दिये ज्ञापन में दर्ज किया है, "२१

फरवरी, १६८५ को डीग में साजिश भरे गोलीकांड में राजां मानसिंह, ठाकुर हरिसिंह व ठाकुर सुमेर सिंह की हत्या हुई थी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री माथुर को जिम्मेवार ठहराते हुए पदमुक्त करवाया था। अब राजीव गांधी ने जांच पूरी होने के पहले माथुर को हत्याकांड के आरोप से दोषमुक्त करार दे दिया और मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया।" ज्ञापन में दावा किया गया है "यह जनभावना के विरुद्ध तो है ही, न्याय की सामान्य प्रक्रिया के भी विरुद्ध है, क्योंकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।" श्रीमती दीपा ने कार्यवाहक राज्यपाल से मानसिंह हत्याकांड की सार्वजनिक जांच के काम को ज़ल्द पूरा करवाने और दोषी लोगों को तुरन्त सजा दिलाने की मांग की है।

विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने इस हत्याकांड पर प्रकाश डालते हुए 'माया' को बताया कि इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की और १८ मई, १६८५ को अदालत में चालान पेश कर दिया। इसमें कुल १८ पुलिसकर्मी दोषी पाये गये, जिसमें एक पुलिस उप अधीक्षक, एक इंसपेक्टर, दो सब इंसपेक्टर, तीन हेड कांसटेबल और दस कांसटेबल शामिल हैं। उनका आरोप था कि सारा प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२, १४७, १४८, १४६, ३२३, १६६, २१८ के तहत देखा गया है, जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जानबूझ कर षड्यंत्र की धारा १२० के तहत कोई जांच नहीं की।

श्री शेखावत का कहना था कि विधानसभा में राज्य सरकार ने १६ मार्च, १६८५ को न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी की, लेकिन बाद में षड्यन्त्रपूर्वक उसको वापिस ले लिया गया। उनके अनुसार श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) के पति व राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने घटना की जो एफ़०आई०आर० दर्ज करवाई थी, उसमें सीधा यह आरोप था कि हत्या योजनाबद्ध थी।

श्री शेखावत का सवाल था कि श्री माथुर को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किस आधार पर दोषमुक्त कर दिया ? उनका मानना है कि पहले इस प्रकरण की न्यायिक जांच करवानी चाहिए और न्यायिक जांच हो, तो श्री माथुर को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए।

इस आन्दोलन के उग्र होने की संभावना चुनावों को नजदीक देखकर और बढ़ जाती है। जाति विशेष की संवेदनाओं को यह घटना आज भी झकझोरती है। शायद यही वजह थी कि केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह ने श्री माथुर को मुख्यमंत्री बनाये जाने पर नाराजगी प्रकट की है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का माथुर मंत्रिमंडल में शामिल न होने की एक वजह यह भी रही है कि उन्हें भरतपुर जिले में पड़ने वाले अपने निर्वाचन क्षेत्र में पैदा हुए जन आक्रोश का भय था।

आलाकमान से दिल्ली में रहने का आश्वासन प्राप्त कर जहां उन्होंने अपने को जन आक्रोश से बचाया है वहीं अपनी वरिष्ठता का भ्रम बरकरार रखा है। बहरहाल, विपक्ष के इस मुद्दे पर एक होने की पूरी सम्भावना है। श्री माथुर को विपक्ष के नेताओं से तालमेल बिठाने में वह महारत हासिल नहीं है जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोशी विख्यात थे। फिर वर्तमान स्थितियों में इस ओर प्रयास करना भी श्री माथुर के लिए जोखिम भरा कदम होगा। श्री जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने का एक बड़ा कारण उनकी विपक्ष के नेताओं से विशेष दोस्ती भी थी।

माथुर की रणनीति : इस खतरे से श्री माथुर कैसे निपटेंगे, इसका थोड़ा सा आभास उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया की नियुक्ति करके दिया है। श्री पिलानिया जाट समुदाय के हैं। इन्हें अपनी विद्वता के कारण जाट समुदाय में सम्मान हासिल है। साथ ही जातीय गौरव के लिए वह विशेष प्रयासरत रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ के संरक्षण में उन्होंने 'स्वामी केशवानन्द स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट' की स्थापना श्री गंगानगर जिले के संगरिया ग्राम में की है। इस ट्रस्ट के तहत ग्रामोत्थान विद्यापीठ चल रहा है जिसमें जाट समुदाय की गहरी रुचि है। श्री पिलानिया की नियुक्ति से पूर्व पुलिस महानिदेशक पद पर पी०सी० मिश्रा काम कर रहे थे। ३१ जनवरी को उनके सेवानिवृत होने पर इस पद के लिए जिन तीन अधिकारियों के नामों की चर्चा थी, उन्हें गौण कर श्री माथुर ने पिलानिया को पुलिस महानिदेशक बना दिया। इस नियुक्ति के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा यह रही है कि श्री पिलानिया जाट बहुल क्षेत्र में उठे आन्दोलन को शांत कर उनकी छवि निखारें।

इस नियुक्ति के साथ ही श्री माथुर ने पहली बार पत्रकारों को बताया कि स्वर्गीय राजा मानसिंह उनके अच्छे मित्र थे और आज भीउनके परिवार का वह मन से सम्मान करते हैं। श्री माथुर के इन विचारों को उनका 'नया पैंतरा' कहा जा रहा है। बहरहाल, जाट समुदाय के रोष से निपटने के लिए उन्होंने पहला प्रशासनिक कदम उठाया है। राजनीतिक स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें पिलानिया की नियुक्ति के साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ और केन्द्रीय कपड़ा मंत्री राम निवास मिर्धा का सहज समर्थन हासिल हो गया। पर जब तक नटवर सिंह का समर्थन उन्हें नहीं मिलता, तब तक राजा मानसिंह की हत्या का मामला उनके लिए समस्या बना रहेगा।

मुख्यमंत्री के लिए जोशी सरकार के दौरान दिया हुआ यह बयान भी समस्या खड़ी करने जा रहा है जिसमें उन्होंने राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उपलब्ध राजस्व में ही केन्द्र के समान वेतन व भत्ते देने की बात कही थी। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महामंत्री राम किशोर अग्रवाल ने प्रदेश के पांच लाख कर्मचारियों की ओर से १८ सूत्री मांगपत्र के लिए १० फरवरी को सांकेतिक हड़ताल की घोषणा कर दी थी। कर्मचारियों की यह सांकेतिक हड़ताल फिलवक्त राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हो रही थी। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रदेश के मुद्दों पर भी सांकेतिक ही रहेगी। अगर यह हड़ताल प्रदेश स्तर पर बरकरार रही, तो माथुर सरकार के लिए यह एक 'निमंत्रित-समस्या' बन जायेगी।

—ओम सैनी

दूसरी खेप : माथुर-मंत्रिमंडल

मानसिंह की हत्या

वह हादसा यों हुआ !

भरतपुर राजघराने के सदस्य और महाराजा बृजेन्द्र सिंह के लघु भ्राता राजा मानसिंह १९५६ से ८४ तक लगातार विधानसभा के सदस्य रहे थे। यों राजघराने के प्रभाव के अलावा उनका व्यक्तित्व भी उनकी अनवरत जीत में सहायक था। सौम्य, नेक और सत्यभाषी होने के अलावा उनमें जाट सुलभ अक्खड़पन भी था, जिसके कारण वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले हिचकते नहीं थे। चाहे कुंवर नटवरसिंह को सरेआम 'नकली कुंवर' कहने का मामला हो या पहाड़िया के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी सीट पर चुनाव लड़ने की पेशकश, राजा मानसिंह सदैव बेलाग और बेलौस ही दिखाई देते थे। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा गुण था राजपरिवार से सम्बद्ध होने के बावजूद सामान्य जन के साथ सहज संबंध। होली पर आम जनता के बीच 'महामूर्ख सम्मेलन' में शामिल होना, दशहरे पर नुमाइश में रात भर जनता के साथ कवि सम्मेलन, कव्वाली सुनना या शहर की चहारदीवारी को बनाये रखने की मांग को लेकर धरना देना, यह सभी उनकी सहजता के प्रमाण हैं और आम आदमी भी उन्हें स्नेह और आदर से 'राजाजी' या 'राजा साहब' कहकर सम्बोधित करता था। लेकिन जिस भरतपुर से राजबहादुर जैसा जन आन्दोलन से जुड़ा राष्ट्रीय नेता लगातार नहीं जीत सका, उसी इलाके के एक हिस्से से 'राजा मानसिंह' का लगातार जीतना कम आश्चर्य की बात नहीं थी। खास तौर पर सामन्ती शक्तियों के ह्रास के दौर में 'राजा मानसिंह' को जीत हासिल करने के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े थे। इसी कारण उनका चुनाव अभियान नाटकीय घटनाओं से भरा रहता। चुनाव जीतने के लिए उन्हें नित नये स्टंटों का सहारा लेना पड़ता। एक स्टंट के पुराने पड़ने पर दूसरा स्टंट, पहले से ज्यादा प्रभावी और प्रचारात्मक।

चुनावी स्टंट: राजा मानसिंह का चुनाव-लड़ने का तरीका बेहद नियोजित था। वह कम-से-कम पैसे में कम-से-कम शक्ति का व्यय करके चुनाव जीत जाते थे। अपनें विधानसभाई क्षेत्र के एक-एक गांव के एक-एक घर के वोटों का हिसाब लगाकर चलते थे। जहां उन्हें वोट मिलने की उम्मीद न होती, वहां वह समय खराब करने में यकीन नहीं करते। गांव में खुद पहुंचने से पहले एक एडवांस पार्टी भेजते जो गांव में घूम-घूमकर उनके आने का प्रचार करती। अपने साथ माइक लगी गाड़ी में लोक गायकों की टोली साथ रखते जो उनकी कीर्ति में रसिया या अन्य लोकगीत गाते हुए चलते थे। दूर से लोग जान जाते कि राजा साहब की गाड़ी आ गयी है। गाड़ी को सारे गांव में घुमाकर सबका अभिनंदन करते। इस अभियान में उनका सबसे बड़ा मकसद होता, नाराज लोगों को येन-केन-प्रकारेण मनाना। सीधे उसके घर जाना और उसे मनाकर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर मीटिंग में ले जाना। गांव के बुजुर्गों के समक्ष राजपरिवार से उनके पारिवारिक संबंधों की दुहाई देकर भावुकतापूर्ण वातावरण बनाना और अन्त में अपनी टोपी उतार कर सामने फैलाने तक उनके चुनावी स्टंटों का अंग हुआ करता। गुर्जरों के बीच वह कहते कि मैंने जन्म जाट के घर लिया है, पर दूध तो गुर्जरी का पिया है। इसी तरह लोगों की भावनाओं को भुनाते वह लगातार जीतते आ रहे थे। अस्सी के चुनाव में भी उन्हें एक स्टंट करना पड़ा था। जब वह चुनाव अभियान के प्रारम्भ में अपने पैतृक गांव सिनसिनी पहुंचे, तो वहां के बुजुर्गों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पर राजा मानसिंह ने गांव का एक चक्कर लगाया और एक बिटौरे (गोबर के कंडों का ढेर, जिसमें से नीचे से कण्डे निकाले जाते हैं जिससे बीच में जगह बन जाती है) में घुस कर बैठ गये। गांव में यह खबर फैलने पर लोग वहां इकट्ठे हो गये और उन्होंने मानसिंह से आग्रह किया कि वह बिटौरे से बाहर आ जायें, पर मानसिंह अड़े हुए थे, "नाएं, आप तौ जा में आग लगाय दो, मैं तो जाइ में मरूंगो। जब आप लोगई मोय नाएं जितानौ चाहौ, तो मैं जी कर क्या करूंगो।" अंत में वह गांव वालों के गंगाजी की कसम खाकर वोट देने के आश्वासन के बाद ही बाहर आये।

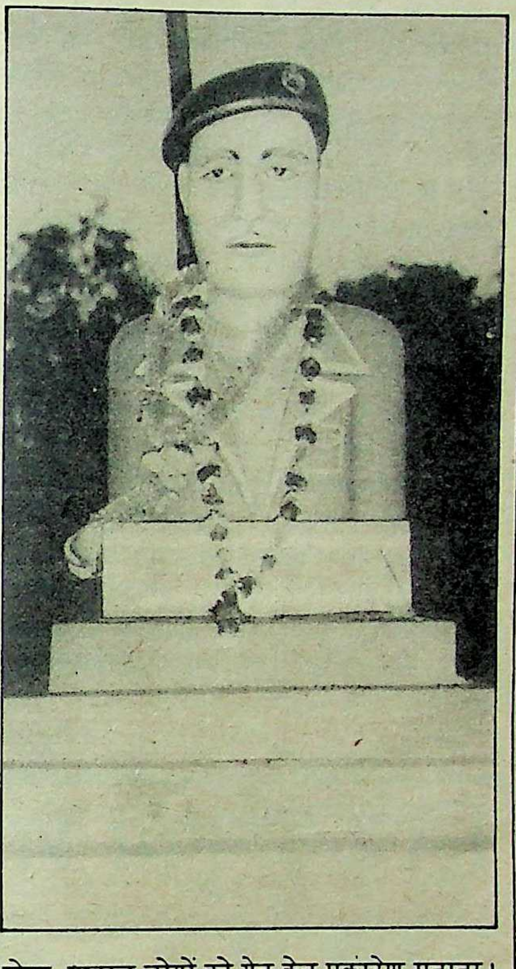

राजा मानसिंह को जीत हासिल करने के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े थे। इसी कारण उनका चुनाव अभियान नाटकीय घटनाओं से भरा रहता। चुनाव जीतने के लिए उन्हें नित नये स्टंटों का सहारा लेना पड़ता। एक स्टंट के पुराने पड़ने पर दूसरा स्टंट, पहले से ज्यादा प्रभावी और प्रचारात्मक।

पचासी के चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनके मुकाबले कांग्रेस-इ ने प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी व जाट उम्मीदवार बृजेन्द्र सिंह को खड़ा किया था। दूसरी ओर नटवरसिंह भी राजा मानसिंह से रुष्ट थे और हर हालत में उन्हें हराना चाहते थे। इसी कारण इंका ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में विपुल साधन झोंक दिये थे। डीग की जनता के लिए ऐसी चकाचौंध वाला प्रचार अभियान एकदम नया ही था। राजा मानसिंह भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। नटवरसिंह तथा बृजेन्द्र सिंह के कारण जाट वोटों के बंट जाने की पूरी आशंका थी और चुनाव में वह कांग्रेसी उम्मीदवार के समान पैसा व्यय कर नहीं सकते थे। उनके सामने एक ही रास्ता था कोई नया और धमाकेदार स्टंट करने का। आखिरकार स्टंट की योजना तैयार हो गयी। वकीलों से राय ली गयी। इस बार स्टंट का निशाना थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर।

२० फरवरी, १९८५ को दोपहर १२ बजे राजा मानसिंह ने अपने नौकर को ऊपर छत पर भेजा कि जैसे ही मुख्यमंत्री का हैलीकाप्टर नजर आये, मुझे सूचित करना। उस समय वह न तो उत्तेजित नजर आ रहे थे और न ही नशे में थे। हैलीकाप्टर के आने की सूचना पाकर वह अपने सहयोगियों के साथ जोंगा जीप में बैठे और उसे खुद चलाते हुए सभा स्थल पर पहुंच गये। आराम से लोगों को मंच से कूद जाने का समय देते हुए मंच को जोंगा की टक्कर से तोड़ दिया तथा उस स्थल की ओर चल दिये जहां हैलीकाप्टर को उतरना था। जब तक मानसिंह वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री माथुर सभा स्थल की ओर रवाना हो चुके थे। उन्होंने हैलीकाप्टर तोड़ा और वापस अपने चुनाव कार्यालय पर आकर सहज भाव से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांवों में मीटिंग करने चले गये। रात को ग्यारह बजे लौट कर आने के बाद उन्होंने वकीलों से मशविरा किया। अपनी मंझली लड़की दीपा तथा दामाद विजय सिंह को चुनाव अभियान चलाते रहने

के बारे में समझाया। हैलीकाप्टर तोड़ने के लिए तर्क ढूंढ़ा गया और पाया गया कि 'झंडे के अपमान' को प्रचारित किया जाये। राजा मानसिंह सारी रात इन्तजार करते रहे कि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने आयें, पर जब सुबह तक कोई गिरफ्तार करने नहीं आया, तो यह मान लिया कि संभवतः सरकार राजनीतिक लाभ-हानि को मद्देनजर रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती।

गिरफ्तारी के आदेश: दूसरी ओर माथुर हैलीकाप्टर और मंच के टूट जाने से क्षुब्ध थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ? जब उनका हैलीकाप्टर उतर रहा था, तो मानसिंह मंच तोड़ रहे थे और जब वह मंच पर थे, तो मानसिंह हैलीकाप्टर तोड़ रहे थे। आखिर मानसिंह उन पर नाराज क्यों हैं? अगर नाराज हैं, तो उनके सामने आते, मंच और हैलीकाप्टर तोड़ने का क्या सबब? क्षुब्ध मन, क्रोधित माथुर बिना एक शब्द बोले वापस लौट आये। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी डांट लगायी गयी तथा मानसिंह को हर हालत में गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये। पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह (सीमा सुरक्षा बल से प्रतिनियुक्ति पर आये थे) ने ठेठ बी०एस०एफ० अंदाज में डीग के डी०एस०पी० कानसिंह भाटी को कड़ी डांट लगायी और मानसिंह को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दे डाले। ऊपर की डांट से त्रस्त और क्रोधित तथा मानसिंह के खौफ से आतंकित कानसिंह भाटी ने मानसिंह को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर लीं तथा चुनाव मीटिंग के लिए डीग में लक्ष्मण मंदिर की ओर जाते मानसिंह को बीच में अनाज मंडी में रोककर गिरफ्तारी देने के लिए कहा। पुलिस की जीप मानसिंह के जोंगा के सामने खड़ी थी और डी०एस०पी० भाटी मानसिंह की बगल में, लेकिन मानसिंह का मानस इस प्रकार गिरफ्तारी देने का नहीं था। वह चाहते थे कि पुलिस उन्हें मीटिंग में भीड़ के सामने गिरफ्तार करके ले जाये, ताकि उनका स्टंट भरपूर असर छोड़ सके। उन्होंने यह कह कर कि 'गिरफ्तार करना है, तो लक्ष्मण मंदिर पर आ जाओ' अपना जोंगा पुलिस की जीप के आगे से निकालने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से जोंगा का बम्पर जीप से उलझ गया और एक झटके से जीप हिल गयी तथा जीप में बैठे पुलिस वाले धड़-धड़ जमीन पर गिर पड़े। एक पल में सबकी समझ में यही आया कि राजा मानसिंह ने जीप पर जोंगा चढ़ा दिया। तभी थानेदार की चीख गूंजी, शायद किसी पुलिस वाले की राइफल उसको लग गयी थी। इतने में एक पुलिस वाले ने राइफल का बैनट जोंगा के अगले पहिए में दे मारा। वातावरण में टायर फटने की आवाज गूंज गयी। ऐसा लगा मानो गोली चली हो।

जीप से पुलिस वालों का गिरना, टायर फटने की आवाज, थानेदार की चीख यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि 'आतंकित, क्रोधित और त्रस्त डी०एस०पी० कानसिंह भाटी समझ ही नहीं पाये कि क्या हुआ? क्षणांश हतप्रभ रहने के बाद वह यही समझ सके कि गोली चली और थानेदार गया काम से, अब दूसरी गोली चलेगी और वह खुद। उत्तेजित भाटी चीख पड़े— फायर...। फिर वह हुआ जिसे राजनीति के इतिहास का काला पन्ना कहा जाता है। निहत्थे राजा मानसिंह को भारतीय पुलिस ने सरे बाजार, दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया।

फायरों की बौछार थमने के बाद भाटी ने आंख खोलकर देखा, तो पाया कि जोंगा में बैठे लोगों की लाशें पड़ी हैं और पुलिस पक्ष में किसी को खरोंच नहीं लगी। मानसिंह पक्ष की ओर से कोई गोली नहीं चली थी। थानेदार मोहन सिंह सही सलामत थे, तो फिर वह क्यों चीखे थे? क्षुब्ध भाटी ने वहीं एक पुलिस वाले की राइफल छीनकर उसके बट से थानेदार की पिटाई कर डाली। इसके बाद जोंगा से लाशों को निकाला गया और तुरंत जीप में डालकर पुलिस दल भरतपुर के लिए रवाना हो गया। देखते ही देखते यह खबर न केवल डीग में, भरतपुर में बल्कि सारे देश में आग की तरह फैल गयी और पुलिस के माथे पर कलंक की तरह सदा-सदा के लिए टंग गयी।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक

रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोजमर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर व नये रक्त के निर्माण द्वारा पूरे शरीर का पोषण करती है। **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा बहुमूल्य जड़ी-बूटियों, केसर, मोती आदि द्रव्यों से निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय, आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो पुरुषों को सदैव निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

200 गोली रु० 82/-, 60 गोली रु० 32/40 स्थानीयकर अलग। स्थानीय विक्रेता से लें या 25/- रु० का मनीआर्डर भेज कर वी.पी. से मंगवायें। वी०पी० खर्च रु० 12/- अलग।

राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
शाखाएं: दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
राजवैद्य
शीतल प्रसाद एण्ड संस
२३ दरियागंज, नई दिल्ली-२

SAMP/22C

सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज

डाक्टरों का राजरोग

देश के एक सौ छह और राजस्थान के पांच मेडिकल कालेजों में आज से ४० वर्ष पूर्व स्थापित सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी ख्याति अर्जित की है। लेकिन हाल में उभरी कुछ डाक्टरों की गुटबंदी से इस प्रतिष्ठित संस्थान का वातावरण अस्वस्थ होने लगा है। इसका सबूत है कालेज के चतुर्दशक समारोह में 'जयपुर फुट' के निर्माण में विशेष सहयोग के लिए सरनाम मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री डा० पी०के० सेठी की उपेक्षा। इस संस्थान में पनप रही राजनीति को अनावृत करने वाली ओम सैनी की रपट :

डा० सेठी की उपेक्षा : उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन, साथ में डा० मेहता

जयपुर का सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज राजस्थान के पांच और देश के एक सौ छह मेडिकल कालेजों में अपना अलग ही स्थान रखता है। अगले तीन वर्षों में यह कालेज स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान (मेडिकल इंस्टीट्यूट) के रूप में देश के चार प्रमुख चिकित्सा सस्थानों की कतार में खड़ा हो जायेगा। सन १९४७ में प्रारम्भ हुए इस मेडिकल कालेज ने अब तक ४ हजार ७४६ चिकित्सक और २ हजार ७० स्नातकोत्तर चिकित्सक दीक्षित किये हैं।

चिकित्सा के लिए विख्यात यह संस्थान पिछले दिनों अपने चार दशक पूरे करने पर मनाये गये समारोह के दौरान डाक्टरों की गुटबन्दी से चर्चा का विषय बन गया है। ५ जनवरी, १९८८ से छह सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति डा० शंकरदयाल शर्मा ने किया था। समारोह के उद्घाटन के दौरान जिस 'जयपुर फुट' की चर्चा के साथ उपराष्ट्रपति ने अपना भाषण समाप्त किया, उसी के निर्माण में सहयोगी पद्मश्री डाक्टर पी०के० सेठी इसमें उपस्थित नहीं थे। डा० सेठी सन १९५५ से लेकर १९८१ तक सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में कार्यरत रहे हैं। 'जयपुर फुट' के निर्माण में प्रमुख सहयोगी भूमिका के लिए उन्हें मेग्सेसे और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

अस्थि विशेषज्ञ डाक्टर प्रमोद करण सेठी की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में जब 'माया' ने आयोजकों से सवाल किया, तो ज्ञात हुआ कि उन्हें बाकायदा आमंत्रित किया गया था। आयोजकों ने डा० सेठी के यहां निमंत्रण प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर भी अपनी पावती पुस्तिका में 'माया' को दिखाया। इसके विपरीत प्रेस से गुरेज करने वाले डाक्टर पी०के० सेठी ने स्थानीय पत्र के एक संवाददाता से स्पष्ट कहा, "मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं समारोह में शामिल नहीं हुआ।" डाक्टर सेठी समर्थक चिकित्सकों का आरोप था कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय और मेडिकल कालेज के प्राचार्य एवं नियन्त्रक पद्मश्री डाक्टर एस०आर० मेहता ने जान-बूझकर ऐसे डाक्टरों को समारोह से परे रखा, जिन्हें वह किन्हीं कारणों से पसन्द नहीं करते।

सम्मान-समारोह : इस अवसर पर एक समारोह में कालेज के पूर्व आचार्यों और विशिष्ट पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया था। इस सम्मान समारोह में भी पद्मश्री डा० सेठी को सम्मानित नहीं किया गया। आयोजकों के सम्मान का मानदड केवल मेडिकल कालेज के पूर्व छात्र थे, जबकि डाक्टर सेठी ने अपनी चिकित्सक डिग्री आगरा मेडिकल कालेज से हासिल की थी। समारोह के आयोजकों ने इसी आधार पर कालेज परिसर में लगे बोर्ड पर पद्मश्री प्राप्त करने वाले उन चिकित्सकों के नाम दर्ज नहीं किये जो इस कालेज के छात्र नहीं थे। यानी विश्वविख्यात डाक्टर सेठी की उपलब्धियों को उन्हीं के शैक्षणिक इतिहास के पूर्व पन्नों पर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। वैसे सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के चार चिकित्सकों को अब्र तक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डाक्टर एन०के० वर्मा को भारत-चीन युद्ध के दौरान सेवाओं के लिए सबसे पहले सन १९८० में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डाक्टर वर्मा आंजकल रोहतक (हरियाणा) में सेवारत हैं। इनके बाद इसी कालेज के डाक्टर बी०के० गोयल आजकल बम्बई के जे०जे० हास्पिटल, बाम्बे हास्पिटल और ग्रांट मेडिकल कालेज से सम्बद्ध देश के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। १९८५ में वर्तमान प्राचार्य डाक्टर एस०आर० मेहता को पद्मश्री का सम्मान हासिल हुआ। पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले इन चिकित्सकों का नाम पट पर वरीयता क्रम से दर्ज होना चाहिए था। डाक्टर मेहता के आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने अपना नाम जान-बूझकर सबसे ऊपर अंकित करवा लिया।

इन सारे एतराजों और नाराजगियों के पीछे मेडिकल कालेज में पनप रही गुटबाजी है। समारोह के दौरान इनकी गोलबंदी हुई और दो गुट उभरकर सामने आ गये। इनमें एक गुट का नेतृत्व सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्राचार्य व सम्बद्ध अस्पतालों के नियंत्रक पद्मश्री डाक्टर एस०आर० मेहता करते हैं। इन्हें राज्य सरकार के चिकित्सा सलाहकार की हैसियत हासिल है। दूसरे गुट में डाक्टर सेठी और एस०एम०एस० के 'यूरालोजी रिसर्च सेन्टर' के प्रमुख डाक्टर के०सी० गंगवाल तथा 'अनुसंधान व पुनर्वास केन्द्र' के प्रोफेसर डाक्टर एस०सी० कासलीवाल शामिल हैं। डाक्टर सेठी ने सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के चिकित्सालय संतोकबा दुर्लभजी में काम करना प्रारम्भ कर दिया है, जबकि उनके गुट के दोनों चिकित्सक सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ही सेवारत हैं।

विवाद का मुद्दा चिकित्सा-व्यवस्था है। डाक्टर एस०आर० मेहता प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को सरकारी सहयोग से जन-जन तक पहुंचाने के हामी हैं, जबकि दूसरा गुट इसका व्यापारीकरण करने का पक्षधर है। यही वजह है कि डाक्टर सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रांगण में महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से निःशुल्क दिये जाने वाले 'जयपुरिया पांव' की जगह निजी क्षेत्र के संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में काम शुरू कर घुटने तक का पांव पांच सौ रुपयों और पूरा पांव आठ सौ रुपयों में बेचना प्रारंभ किया है। इसके विपरीत डाक्टर एस०आर० मेहता इस मुद्दे पर एस०एम०एस० प्रांगण में महावीर विकलांग सहायता समिति की गतिविधियों के समर्थक हैं।

इसी तरह डाक्टर के०सी० गंगवाल अपनी चिकित्सा निपुणता का सहज लाभ आम आदमी को उपलब्ध कराने के पक्षधर नहीं हैं। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जयपुर के निजी क्षेत्र के चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टर छजलानी अल्प साधनों से गुर्दारोपण का काम अंजाम दे रहे हैं,

साक्षात्कार/डा०एस०आर० मेहता

डाक्टर सेठी आमंत्रित थे

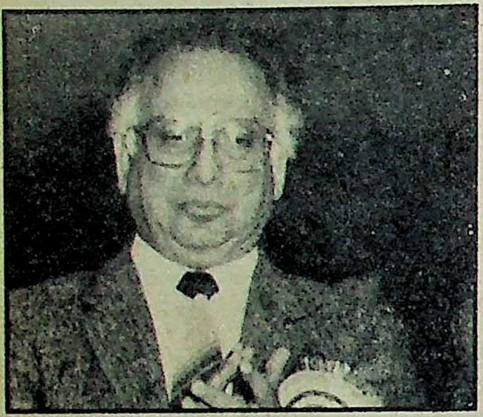

सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद्मश्री डाक्टर एस०आर० मेहता अपने फन में उस्ताद होने के साथ-साथ अपने हक हासिल करने के मामले में बड़े सजग हैं। यही वजह है कि गुटबंदियों का जवाब देने अथवा उपलब्धियों का प्रचार करने में वह कहीं पीछे नहीं रहे है। समारोह के दौरान उत्पन्न विवादों का कारण जानने के लिए 'माया' ने उनका साक्षात्कार लिया। प्रस्तुत हैं, साक्षात्कार के कुछ अंश :

माया: आपने कालेज के चालीस साल पूरे होने पर क्यों समारोह आयोजित किया, जबकि पचास वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाने का अवसर बनता था?

मेहता: एस०एम०एस० की स्थापना देश की आजादी के साथ ही हुई थी। जिस तरह से आजादी के चालीस साल पूरे होने के समारोह मनाये जा रहे हैं, वैसे ही एस०एम०एस० के चतुर्दशक समारोह मनाने का निर्णय हुआ। वैसे भी हमने कालेज के बीस साल पूर्ण होने पर १९७७-७८ में समारोह मनाया था। सिल्वर अथवा गोल्डन जुबली मनाने जैसी परंपरा इसमें आड़े नहीं आती।

मांया: आपने इस समारोह में 'जयपुर फुट' के निर्माण में सहयोगी डाक्टर पी०के० सेठी को क्यों नहीं आमंत्रित किया?

मेहता: डाक्टर सेठी को निश्चित रूप से आमंत्रित किया गया था। उनका निमंत्रण-पत्र उनके कार्य स्थल संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे रिसीव (प्राप्त) किया गया। रिसीव होने के बाद रिसीव करने वाले ने उन्हें उसे दिया या नहीं दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पर उन्हें आमंत्रित जरूर किया गया था।

माया: एक स्थानीय पत्र के संवाददाता से तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला?

मेहता: प्रेस में आये इस बयान का खंड़न हमारे आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डाक्टर धारकर ने उस अखबार के संपादक को पत्र लिख कर किया है। यह खंडन उस अखबार में प्रकाशित भी हुआ है।

माया: डाक्टर सेठी को पद्मश्री से सम्मानित उनके एस०एम०एस० में कार्यरत रहते हुए किया गया था फिर भी उनका नाम परिवार में लगे उस पट पर दर्ज नहीं है जिस पर पद्मश्री प्राप्त करने वालों के नाम लिखे गये हैं?

मेहता: एस०एम०एस० मेडिकल कालेज में लगे बोर्ड पर केवल कालेज के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को ही दर्ज किया गया है। डा० सेठी एस०एम०एस० के पूर्व छात्र नहीं हैं। डा० सेठी ने अपनी डिग्री आगरा मेडिकल कालेज से प्राप्त की है।

माया: समारोह के दौरान आपके 'यूरोलाजी रिसर्च सेंटर' की बड़ी चर्चा रही, पर साधन संपन्न होने पर भी यह 'गुर्दारोपण' में क्यों पीछे है?

मेहता: हमारा यूरोलाजी सेंटर अच्छा काम कर रहा है। विशेष रूप से ट्रांस्यूरेथरल सर्जरी जो कि अमरीकी डाक्टर मिनरा की मदद से यहां स्थापित हुई थी। आज यह ट्रांस्यूरेथरल सर्जरी का अच्छा सेंटर बन गया है। हमारे यहां गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन (रोपण) की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विभाग के लोग भविष्य में किडनी ट्रांस्प्लान्ट करने में सक्सेजफुल (सफल) होंगे।

माया: डा० के०सी० गंगवाल तो इस विषय में काफी अनुभवी हैं, फिर उन्होंने इस ओर क्यों नहीं प्रयास किया?

मेहता: मेरा खयाल है कि यह डाक्टर गंगवाल से ही पूछें, तो ठीक रहेगा। मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे यहां काफी अरसे से सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो सुविधाएं डा० छजलानी के पास हैं, वह तो कई वर्षों से एस०एम०एस० में हैं। विशेष सुविधाओं को हम औपचारिक रूप से आज न भी मानें, पर अनौपचारिक रूप से तो उन्हें हासिल किये बहुत समय हो गया।

माया: 'भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति' के कर्मचारियों के असंतोष की वजह क्या है?

मेहता: मुझे इसका विस्तार से कोई ज्ञान नहीं है, पर मैंने उपराष्ट्रपति डा० शंकरदयाल को इस संमिति की कार्यशाला दिखाने का कार्यक्रम बनाया था। पर एक तो उपराष्ट्रपति के पास समय कम था और दूसरे कुछ तत्वों ने कार्यक्रम की सूचना के साथ ही वहां अशांति फैलाने की कोशिश शुरू कर दी थी, इसलिए ऐसा नहीं हो सका।

माया: विकलांगों की प्रवक्ता, सर्वोदय विकलांग समिति का आरोप है कि इस असंतोष के लिए आपका अस्थि विभाग जिम्मेदार है?

मेहता: एस०एम०एस० चिकित्सालय के अस्थि विभाग के प्रमुख डा० उपाध्याय हैं। डा० उपाध्याय भगवान महावीर विकलांग समिति के कार्यों की तारीफ करते हैं और खुद उसमें रुचि लेते हैं। फिर भी हो सकता है कुछ लोग स्वार्थवश गड़बड़ करते हों। हमारा चिकित्सालय तो उनके सहयोग के लिए शुक्रगुजार है।

माया: डाक्टर सेठी के इस समिति से अलग होने का कारण आप बता सकते हैं?

मेहता: मुझे विशेष तो कुछ नहीं कहना, पर डाक्टर सेठी जब यहीं आनरेटी डायरेक्टर (मानद निदेशक) थे, तो वहां कभी भी गये नहीं।कभी आउटडोर आये भी नहीं। तीन साल का साथी तो मैं हूं। वह अपने कार्यों में शायद बहुत व्यस्त रहते हैं। यही वजह रही होगी कि वह अलग हो गये।

माया: भगवान महावीर विकलांग समिति को एस०एम०एस० चिकित्सालय कोई आर्थिक सहायता प्रदान करता है?

मेहता: नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं देता। हमारे माध्यम से केवल मरीजों का इलाज होता है। हम तो आज अपने चिकित्सालय में ऐसी चालीस वालंटियरी एजेंसियों का सहयोग ले रहे हैं, जिनसे हम मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देते हैं। मैं मानता हूं कि सारा भार राज्य सरकार पर नहीं डाला जा सकता। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए समाज के गणमान्य लोगों और संस्थाओं का सहयोग बहुत जरूरी है। रक्तदान जैसे काम में आज साठ संस्थाएं जुटी हैं। इसका परिणाम यह निकला है कि एस०एम०एस० में कभी रक्त की कमी नहीं रहती।

माया: जीवन विज्ञान प्रदर्शनी में शवों को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया, उसे आप औचित्य पूर्ण मानते हैं?

मेहता: डेड बाडीज (शवों) को मेडिकल साइंस में अनाटमी विषय के तहत चीरना-फाड़ना जायज है। फिर जो डेड बाडिज प्रदर्शित की गयीं, वे आजकल की नहीं थीं। हमने उनका ममीफिकेशन कर दिया था। इनमें कुछ को तो हमने १९५३ से सुरक्षित रखा हुआ है। ममीफिकेशन की हुई इन डेड बाडीज का प्रदर्शन शिक्षा के लिए अनुचित नहीं कहा जा सकता।

—ओम सैनी

मार्च प्रथम अंक १९८८

मनोरमा

मातृत्व और शिशुचर्या

विशेषांक

हर नई मां के लिये एक अनुपम भेंट

अंक के विशेष आकर्षण

- आनेवाले बच्चे की जिम्मेदारी से घबराहट क्यों ?
- पहचानिए जुबान गोद के बच्चे की
- शुरू के तीन वर्षों में बच्चा बहुत कुछ सीखता है
- जन्मोपरान्त बच्चों की आम बीमारियां
- बच्चों का फैशन
- बच्चों का फर्नीचर
- यदि पुरुष जन्म देने लगें
- मत कीजिए बच्चों के पैरों की उपेक्षा
- रोना सिर्फ बच्चे का हथियार ही नहीं
- दांत निकलते समय क्या सावधानियां बरतें ?

आवरण कथा

प्रसव के बाद यौन सुख : बच्चे के जन्म के बाद दम्पतियों को अक्सर यह महसूस होने लगता है, कि उनकी सेक्स लाइफ पहले जैसी नहीं रही। पर यदि थोड़े धैर्य और समझदारी से काम लिया जाय तो प्यार भरी जिन्दगी पुनः वापस लौट सकती है।

- मां बनने के बाद भी आप एक पत्नी हैं
- मातृत्व और मधुमेह
- ये सुपर मम्मियां...
- बेटी की चाह में हो गये ग्यारह बेटे
- सिजेरियन क्यों बढ़ते जा रहे हैं ?
- नयी मां के लिए गुन की पिटारी

साथ ही कहानी, हास्य-व्यंग्य और सभी नियमित स्तम्भ !

मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रकाश्य

मूल्य-६.००

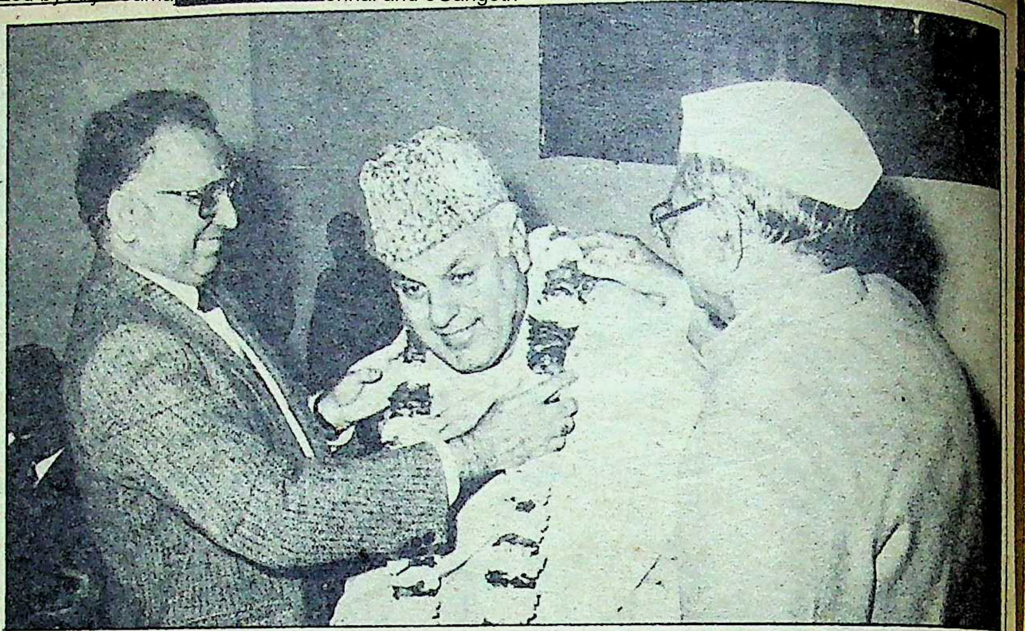

पूर्व छात्र का सम्मान : बायें से प्राचार्य डा० एस०आर० मेहता, डा० फारूख अब्दुल्ला (बीच में)

जबकि डाक्टर के०सी० गंगवाल ज्यादा अनुभवी होने और चिकित्सा उपकरणों से संपन्न होने के बावजूद गुर्दारोपण के प्रयास से परे रहे हैं।

डाक्टर सेठी की मान्यता वाले डाक्टर गुणवत्ता को बनाये रखने के नाम पर धनी लोगों तक अपने चिकित्सा चातुर्य को सीमित रखना चाहते हैं, जबकि डाक्टर एस०आर० मेहता इसे आम आदमी को उपलब्ध करवाने के हामी हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के चतुर्थ दशक समारोह के दौरान इसी के परिणामस्वरूप डाक्टर सेठी की अवधारणा वाले डाक्टरों को केवल 'जरूरी' सम्मान ही दिया गया। मसलन, 'यूरोलाजी रिसर्च सेन्टर' के प्रमुख डाक्टर के०सी० गंगवाल को राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की फेलोशिप हासिल करने के लिए ही सम्मानित किया गया, जबकि १९८१ में उन्हें बी०सी० राय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। इसी तरह राजनीति में महारत हासिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री डा० फारूख अब्दुला को पूर्व छात्र के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन निजी क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले, जनता सरकार में मंत्री रहे पूर्व छात्र डा० हरिसिंह को नजरंदाज कर दिया गया।

हड़तालों का सिलसिला : इस समारोह के दौरान डाक्टर एस०आर मेहता की योजना थी कि 'भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति' के काम को उपराष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा को दिखाया जाये। कहा जाता है कि जैसे ही इस योजना का आभास सेठी-समर्थकों को हुआ, उन्होंने समिति में कार्यरत चालीस कर्मचारियों के वेतन के मामले को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन का सिलसिला शुरू करवा दिया। दरअसल समिति की पांव बनाने की निर्माणशाला में कार्यरत चालीस कर्मचारियों में से २० सरकारी कर्मचारी हैं और बाकी बीस समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन और सुविधाएं हासिल होती हैं, वे समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को हासिल नहीं होतीं। 'माया' ने समिति में कार्यरत कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डालचंद से बात की, तो ज्ञात हुआ कि उनके साथियों को पांच सौ रुपयों से ज्यादा पगार नहीं मिलती, जबकि सरकारी कर्मचारियों को नौ सौ रुपए और अन्य सुविधाएं हासिल होती हैं। यूनियन का यह भी आरोप है कि उनके साथ कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, जबकि उसी काम को करने वाले अन्य कर्मचारी को कम वेतन दिया जाता है। आन्दोलन के इसी दौर में समिति के सचिव एवं आई०ए०एस० अधिकारी डी०आर० मेहता ने जब विकलांगों के संबंध में यूनियन नेताओं के भद्दे आरोप सुने, तो एक नेता की बांह पकड़कर जानना चाहा कि वे किस के इशारे पर भद्दी बात कह रहे हैं। यूनियन नेताओं ने इसको कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला बना लिया और राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ को अपनी बागडोर सौंप दी।

वस्तुस्थिति जानने के लिए माया ने श्री मेहता से संपर्क किया, तो पता चला कि समिति जिस सेवा भाव से कार्य करना चाहती है, वह डा० सेठी के गले नहीं उतर रहा है। यही वजह रही कि उनके सहयोगी डा० कासलीवाल जैसे अन्य लोग कर्मचारियों के मन में सेवा भाव की जगह लोभ-लालच का विष फैला रहे थे। दरअसल, श्री मेहता विकलांगों के लिए व्यावहारिकता की हद से परे हट कर सोचते हैं। उनके लिए विकलांगों की सेवा से पहले कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में सोचना मुश्किल नजर आता है। वह कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग को एक साजिश समझते हैं, जबकि अल्प वेतन में कर्मचारियों का जीवन दूभर नजर आता है। सिद्धांत और व्यवहार का यह झगड़ा इन पंक्तियों के लिखे जाने तक समझौता-वार्ता में बदल रहा था।

विवादों से चर्चित सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज का चतुर्दशक समारोह इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह के लिए विशेष रूप से याद किया जायेगा। डा० मेहता ने अपने प्राचार्य काल में चिकित्सालय के विस्तार के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के संपन्न लोगों से पैसा हासिल करने में विशेष दक्षता दिखायी है। इस अवसर पर समारोह की चकाचौंध से जहां उन्होंने आने वाले तीन सालों में सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज को स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान में बदलने के लिए सरकार से डेढ़-करोड़ रुपयों का आश्वासन हासिल कर लिया, वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री डा० फारूख अब्दुल्ला को दिलचस्प सम्मान देते हुए पांच लाख का चेक प्राप्त कर लिया। डा० फारूख एस०एम०एस० मेडिकल कालेज के ऐसे स्नातक हैं जिसने इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा समय लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। हालांकि समारोह के आयोजक उनके इस कीर्तिमान के आंकड़े देने को उत्सुक नजर नहीं आये। बहरहाल, देश के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए एक सर्वोत्तम छात्र के नाते उनका सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान डा० अब्दुल्ला ने डा० मेहता की अपेक्षा के अनुरूप एस०एम०एस० को स्नातकोत्तर संस्थान बनाने की बात कहते हुए पांच लाख रुपयों की सहायता की घोषणा कर दी।

समारोह में उपस्थित चिकित्सकों का दर्द समझते हुए डा० फारूख अब्दुल्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की उपस्थिति में सुझाव दिया कि मेडिकल कालेज को स्नातकोत्तर संस्थान बनाने पर इसकी स्वायत्तता विश्वविद्यालय जैसी ही होनी चाहिए तथा डाक्टरों को वेतन, भत्ते आदि ऐसे दिये जायें जिससे उनके मन में विदेश जाने का मोह समाप्त हो। मेडिकल कालेज की गुटबंदियों से अनभिज्ञ डा० अब्दुल्ला ने भी 'जयपुरिया पांव' एवं एस०एम० एस० के 'यूरालाजी रिसर्च सेन्टर' की खुलकर तारीफ की और कहा कि मानव कल्याण की दिशा में हुए इन महत्वपूर्ण कार्यों ने संस्थान का नाम रोशन किया है।

बावजूद व्यवधानों और गुटबंदियों के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में आयोजित इस समारोह के दौरान 'जीवन विज्ञान प्रदर्शनी' आयोजित की गयी। २३ दिन तक चली इस प्रदर्शनी को जयपुर के लगभग तीन लाख लोगों ने देखा। इस प्रदर्शनी में शरीर की विभिन्न क्रियाओं, बीमारियों, उनसे बचने के उपायों तथा चिकित्सा विज्ञान के आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित किया गया था। मानव कंकालों के सहयोग से हर रोग और व्यसन के अंजाम दर्शाये गये थे। पर यहीं एक खटकने वाली बात फार्मोलीन रसायन में अध्ययन के लिए सुरक्षित शवों को 'कुम्हार' और 'दुल्हन' के रूप में सजाकर प्रदर्शित करना था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि शवों के इस प्रदर्शन पर किसी भी खास एवं आम आदमी ने कोई एतराज नहीं किया। निश्चित रूप से यह शव लावारिस लोगों के थे, अन्यथा वारिस लोगों के शवों को तो चन्दन-दाह देने की चेष्टा की जाती है।

■

अब्दुल्ला ने
०एम०एस०
कहते हुए
गा कर दी।
कों का दर्द
तत्कालीन
में सुझाव
तर संस्थान
नय जैसी ही
ति आदि ऐसे
ाने का मोह
टबंदियों से
पांव' एवं
सेन्टर' की
कल्याण की
ान का नाम

ायों के सवाई
ोजित इस
प्रदर्शनी
इस प्रदर्शनी
देखा। इस
बीमारियों
विज्ञान के
गया था।
र व्यसन के
टकने वाली
नए सुरक्षित
में सजाकर
यह थी कि
एवं आम
श्चित रूप से
ारिस लोगों
चेष्टा की

कोई न कोई 'सरप्राइज़' चीज़ जरूर रख देती हूं. अब पता नहीं इत्तफाक है या मेरे पतिदेव जानबूझ कर ऐसी हरकत करते हैं, कि जिस दिन मैं चीज़ भेजना भूल जाती हूं, श्रीमानजी भी लंच लेना भूल जाते हैं.

उन्हें खुश करने के लिए, मैंने तो चीज़ के कुछ ऐसे स्वाद भरे व्यंजन खोज निकाले हैं कि दफ्तर में उन्हें औरों के लिए फुर्सत मिले या न मिले, इस चीज़ के लिए 'वे' वक्त निकालते ही हैं.

वेजिटेबल चीज़ कटलेट

(१० की सामग्री)

३ बड़े आलू-उबालकर छीले और कुचले हुए; १००-१०० ग्राम गाजर, बीन्स, फूलगोभी, पत्तागोभी—सभी बारीक कटे हुए; १०० ग्राम मटर—छिली हुई; १०० ग्राम अमूल चीज़—किसी हुई; १ चम्मच नमक; १/२ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च; ३ चम्मच पिसा धनिया; १ चम्मच गरम मसाला; १ चम्मच जीरा; १ चम्मच सरसों के दाने; २ हरी मिर्च-कटी हुई; १ गड्डी हरा धनिया; १/२ नींबू का रस; वनस्पति-घी-फ्राई करने के लिए.

एक भारी कड़ाही में २ बड़े चम्मच वनस्पति-घी गरम कर लें. इसमें जीरा और सरसों डालकर भून लें और दूसरे मसाले और नमक भी डाल दें. कुछ सेकेंड तक फ्राई करें और कटी हुई सब्जियां और मटर भी डाल दें. अब काफी पानी डालकर इस मिश्रण को पका लें. आंच से उतारकर, कसी हुई चीज़ डाल लें. इस मसाले को अलग रख दें. अब कुचले हुए आलुओं में नमक, नींबू का रस, धनिया और हरी मिर्च मिला लें. आलुओं के इस मिश्रण के, नींबू के बराबर गोले बना लें. हर गोले को हथेली से दबाकर पूरी की तरह चपटा करें और वेजिटेबिल चीज़ का बनाया हुआ मसाला रखकर दूसरी चपटी की हुई आलू की पूरी उसके ऊपर रखें और किनारे दबा दें. अब डबलरोटी के चूरे में थपथपा कर कटलेट को सुडौल आकार दे दें. तवे पर घी डालकर कटलेटों को शैलो-फ्राई कर लें. दोनों तरफ पलटें ताकि करारे और लाल-लाल सिक सकें. चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें.

दफ़्तर में मेरे शौहर से ज़रूर मिलती है, स्वादिष्ट चीज़...अमूल चीज़.

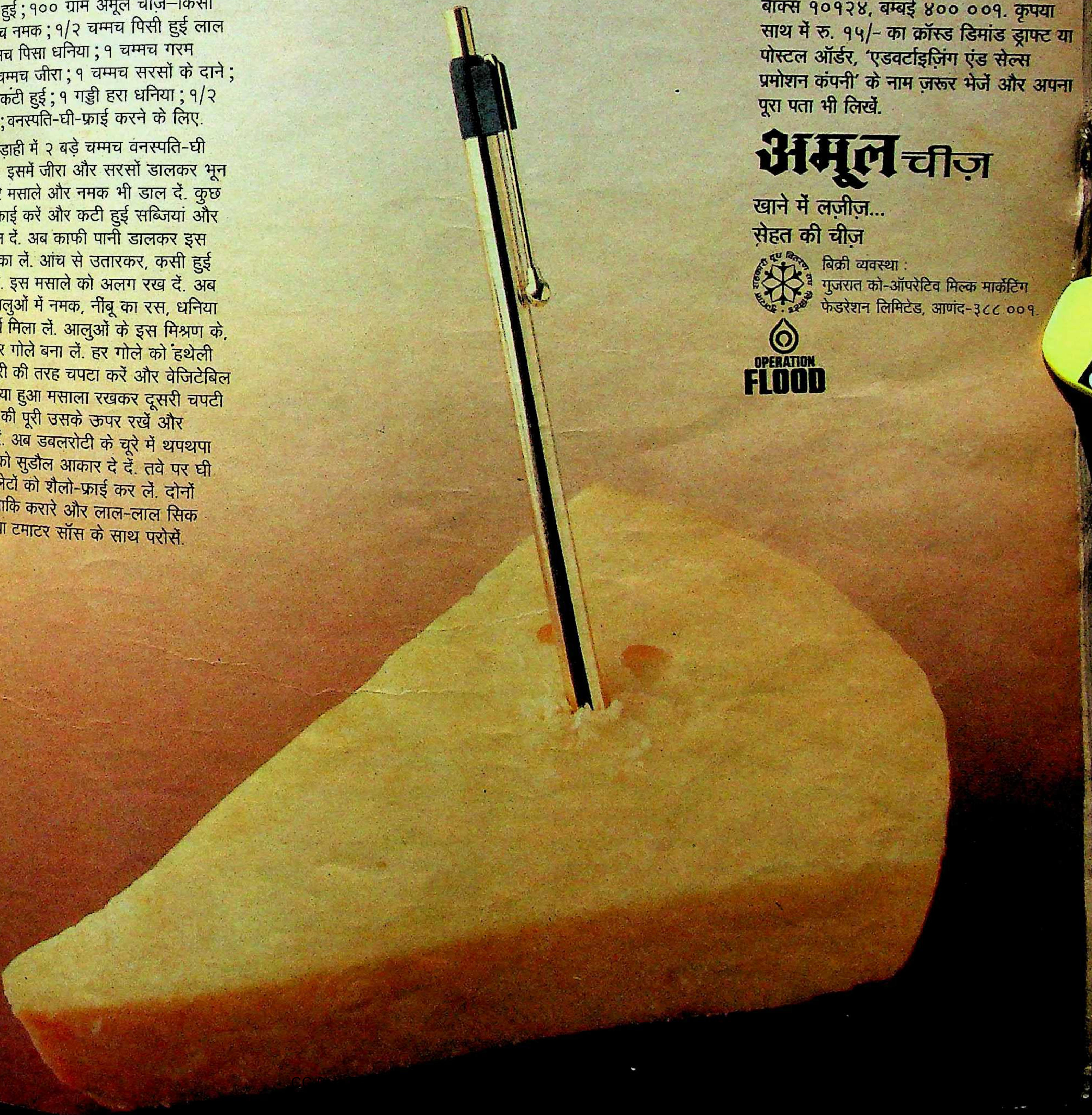

(१० टिकियों के लिये सामग्री)

१/२ कि.ग्रा. आलू—उबालकर छीले और कुचले हुए; १ बड़ा चम्मच सींगदाना—भूनकर छिला और पिसा हुआ; ४ बड़े चम्मच साबुदाना—१/२ घंटे तक पानी में भीगा हुआ; १०० ग्राम अमूल चीज़—कसी हुई; १ या २ हरी मिर्च—कटी हुई; १/२ छोटी गड्डी हरा धनिया—कटा हुआ; वनस्पति घी—तलने के लिए

साबुदाने में से पानी निचोड़ लें और सारी सामग्री अच्छी तरह मिला लें. पतली-पतली गोल टिकियाएं बनाकर तवे पर घी में तब तक सेकें जब तक करारी और लाल न हो जायें. फौरन गर्म-गर्म परोसें.

चीज़ के १२० स्वादिष्ट व्यंजनों की 'अमूल चीज़ पुस्तिका' (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध) मंगाने के लिए इस पते पर लिखें : पो.ऑ. बॉक्स १०१२४, बम्बई ४०० ००१. कृपया साथ में रु. १५/- का क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, 'एडवर्टाइज़िंग एंड सेल्स प्रमोशन कंपनी' के नाम ज़रूर भेजें और अपना पूरा पता भी लिखें.

अमूल चीज़

खाने में लज़ीज़...
सेहत की चीज़

बिक्री व्यवस्था :
गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आणंद-३८८ ००१.

OPERATION
FLOOD

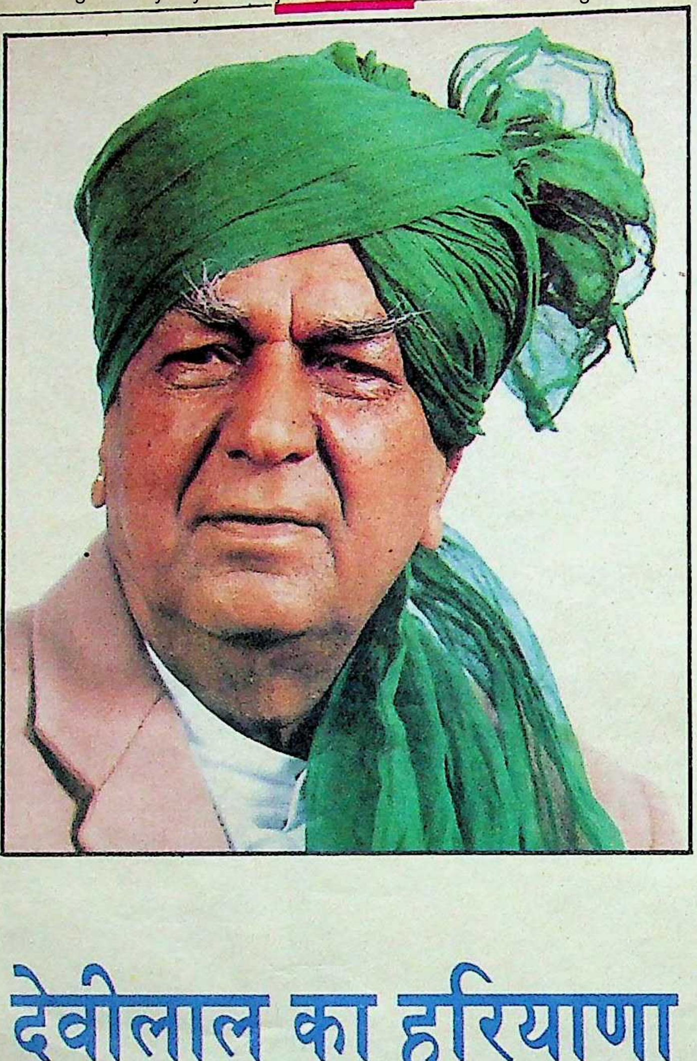

देवीलाल का हरियाणा

आक्रमण चौतरफा है। एक तरफ भ्रष्टाचार और कथित आर्थिक घोटाले हैं, तो दूसरी ओर भाई-भतीजावाद के बोलबाले की चर्चा। प्रशासन के लचर होने के आरोप तो हैं ही, साथ ही बेटों के हस्तक्षेप और आपसी रस्साकशी के अनगिनत किस्से भी मशहूर हुए हैं। परिणामस्वरूप लोकलाज से लोक राज चलाने का डंका पीटने वाले, अपार बहुमत से विजयी, साढ़े छह फुटे, ७६ वर्षीय मुख्यमंत्री देवीलाल एकाएक रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या देवीलाल पर अभूतपूर्व विश्वास प्रकट करने वाली राज्य की जनता की समूची आशाओं-आकांक्षाओं पर अंततः तुषारापात हो जायेगा। क्या उन पर लगाये जा रहे आरोप मात्र पांच विधायकों तक सीमित हो जाने वाली कांग्रेस का कुप्रचार मात्र है अथवा इनमें न्यूनाधिक सचाई है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष को हरियाणा में मिली ऐतिहासिक विजय के सहारे हिंदीभाषी क्षेत्र में कांग्रेस के विकल्प की जो किरण दिखायी पड़ी थी, क्या वह घोर अंधकार में विलीन हो जायेगी?

सूरजकुंड के बहुचर्चित, बहुप्रचारित १५ दिवसीय हस्तशिल्प मेले का एक फरवरी '८८ को उद्घाटन करते समय मुख्यमंत्री देवीलाल ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि राज्य के छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया यह मेला उनके अल्पकालिक शासन काल पर एक सांकेतिक टिप्पणी सिद्ध होगा। राजधानी दिल्ली के संभ्रांत परिवारों के जो लकदक लोग कारों से सूरजकुंड पहुंच महंगी चीजें खरीदते मेले का सुख लूटते थे, उन्हें इस मेले में एक दिन मुफ्त नाटक देखने को भी मिल गया। जनता पार्टी के चर्चित नेता स्वामी अग्निवेश पत्थर खदान की ऐसी दर्जनों महिला श्रमिकों के साथ वहां सहसा जा पहुंचे, जिनके सिर पर खाली घड़े थे। महिलाएं नारे लगा रही थीं—'हमें मेला नहीं, पानी दो।'

'बिजली पानी का प्रबंध, भ्रष्टाचार बंद' जैसे लोकप्रिय नारों के सहारे लगभग सात माह पूर्व सत्तारूढ़ हुई देवीलाल की सरकार के लिए इससे ज्यादा घातक सांकेतिक टिप्पणी और क्या हो सकती है? यदि यह मान भी लिया जाये कि यह प्रदर्शन

लोकप्रियता कसौटी पर : एक जनसभा को संबोधित करते हुए देवीलाल

पूर्वनियोजित और आत्मप्रचार के उद्देश्य को लेकर किया गया था, तो भी इसे चेतावनी न मानना हानिकर सिद्ध हो सकता है। भयंकर सूखे के दैवी प्रकोप और केन्द्र के रोष एवं उपेक्षा की मार को तो हरियाणा सरकार किसी तरह झेल रही थी, किंतु इस फैलते असंतोष और आरोपों की बौछार ने एकाएक उसके सुदृढ़ आधार पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

किसी भी सरकार के लिये जनता की समस्त मांगों, आशाओं अथवा अपने ही चुनावी वायदों को पूरा करना असंभव होता है। यही कारण है कि समय के साथ प्रत्येक सरकार की लोकप्रियता कुछ कम अवश्य हो जाती है। हरियाणा की देवीलाल-सरकार पर भी यह बात उतनी ही लागू होती है, जितनी कि अन्य सरकार पर।

व्यक्तिगत रूप से अर्धशतक से भी अधिक समय राजनीति और जनसेवा में लगाने वाले देवीलाल की ओर आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। देवीलाल के इस लम्बे समय तक लोकप्रिय जननेता बने रहने का राज भी यही है, किंतु जमीन से जुड़े इस नेता की प्रशासनिक ढिलाई और परिवारवाद ने दलदल में कुछ ऐसा फंसाया है कि उसकी आंधी में शून्य हुए विपक्ष को भी बैठे-बिठाये कीचड़ उछालने और लांछन लगाने का सुअवसर प्राप्त हो गया है।

देवीलाल के गांव तेजाखेड़ा के एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता ने 'माया' से कहा, "देवीलाल विपक्ष के तो धाकड़ और दिग्गज नेता रहे हैं, किंतु राजकाज उनके बस का नहीं। वह अकालियों की तरह आंदोलन तो चला सकते हैं, लेकिन शासन नहीं।" देवीलाल के प्रशासन-कौशल के संबंध में केवल कांग्रेस ही ऐसी राय नहीं रखती, शिक्षित वर्ग विशषकर-बुद्धिजीवी और अधिकांश अधिकारीगण भी उनकी इस कमी को बखूबी जानते-पहचानते हैं। राज्य के एक पूर्व कांग्रेसी मंत्री के अनुसार, "प्रशासन वह घोड़ा है जो अपने पीठ पर बैठते ही सवार को पहचान जाता है।" देवीलाल के ढीलेढाले प्रशासन से आज अधिकारी और अन्य स्वार्थी तत्व भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

चंडीगढ़ स्थित राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न लिखने के अनुरोध सहित 'माया' को बताया, "देवीलाल आज एक फैसला लेते हैं, कल उसकी जगह दूसरा। उनकी उस अनोखी कार्यशैली की कीमत हम अधिकारियों को चुकानी पड़ती है। वह कब किस लहर में बहकर अपना कौन-सा आदेश बदल दें, यह कहा नहीं जा सक़ता। यही कारण है कि उनके आदेश-निर्देश का पालन करते समय अनेक अधिकारिंयों के हाथ-पांव फूल जाते हैं।"

२५ जनवरी को भ्रष्टाचार के आरोप में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डा० रूप नारायण शर्मा को हठात हटा दिया गया। बर्खास्तगी आदेश आपातकालीन निर्देश के रूप में रात को ही जारी कर दिये गये थे, किंतु एक फरवरी को शर्मा पुनः अपनी कुरसी पा गये।

बहुरंगी नीति: देवीलाल की इस बहुरंगी नीति के कई कारण गिनाये जाते हैं। एक तो उनका बुढ़ापा जिसमें याददाश्त बुरी तरह आड़े आती है। कब, किससे, क्या कहा, उन्हें स्वयं भी स्मरण नहीं रहता। दूसरे वह कान के कच्चे भी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनके सलाहकारों की लम्बी टोली उनके इर्दगिर्द अपना जाल फैला, उल्लू सीधा करने में जुटी रहती है। देवीलाल की सहृदयता का भी लोग प्रायः अनुचित लाभ उठाते हैं। कहा जाता है कि 'देवी (लाल) के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।' इस संबंध में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है।

चंडीगढ़ के सत्ता गलियारों में एक अन्य उदाहरण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि एक पुलिस अधिकारी को देवीलाल के आदेशानुसार निलंबित किया गया। किंतु उसने सीधे मुख्यमंत्री के पैर पकड़ लिये। आदेश वापस ले लिया गया।

बुद्धिजीवी भले ही देवीलाल की प्रशासनिक ढिलाई का रोना रोयें, आम जनता पर इसका पूर्णतया विपरीत प्रभाव है। उनके बीच देवीलाल की ऐसी छवि स्थापित है कि वह समस्त दोष अधिकारियों पर मढ़ते हुये देवीलाल में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं। सिरसा के एक किसान मांगेराम ने कहा, "सब गड़बड़ अफसरान और नीचे वाले करते हैं। देवीलाल को तो पता ही न होगा। उन्हें जो मालूम हो, तो दूध-का-दूध, पानी-का-पानी कर दें।"

वरिष्ठ हंरिजन नेता व उद्योगमंत्री कृपाराम पुनिया ने लगभग यही बात दोहराते हुए 'माया' से कहा, "हमारी सरकार बंसीलाल की तरह लाठी के बल पर और भजनलाल की भ्रष्टाचार के बलबूते

फ़्लेअर के संग, उमंग ही उमंग!
GOLDEN'S
FLAIR
DELUXE FILTER

वैधानिक चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

Govan/FDF/L/2/87/HN

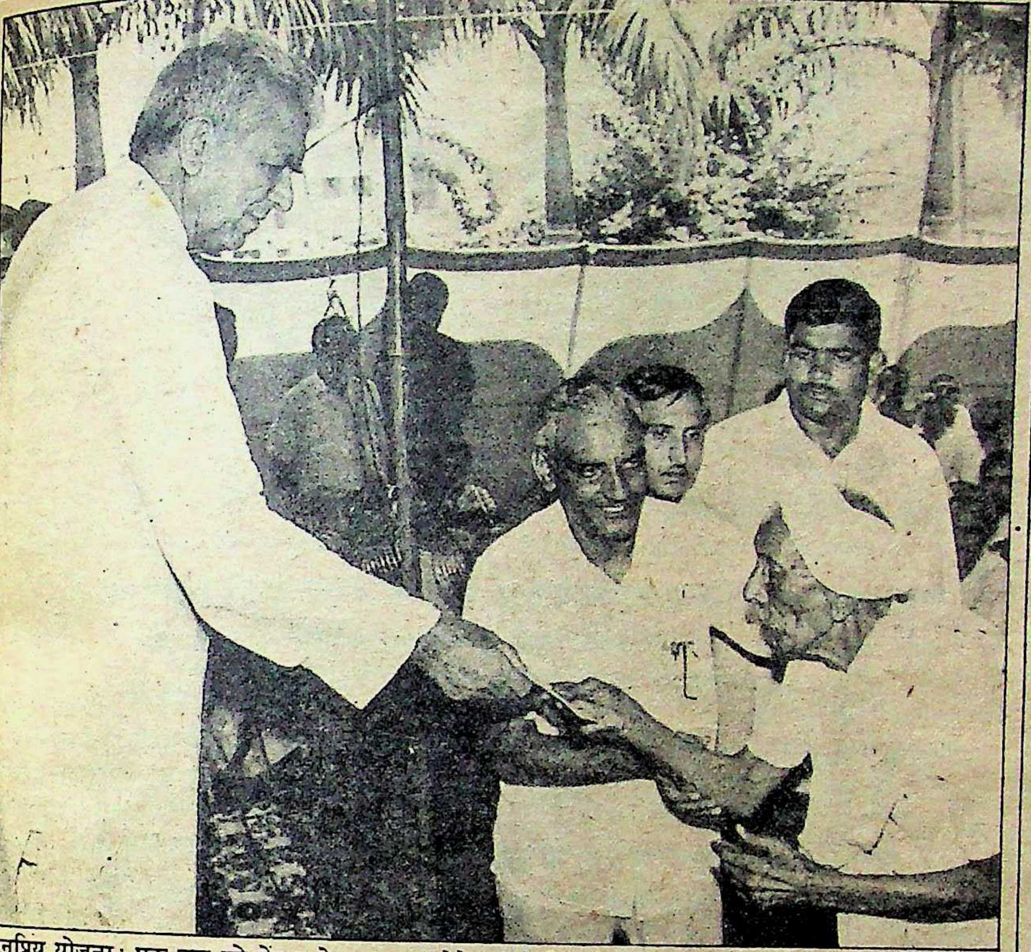

जनप्रिय योजना: एक वृद्ध को पेंशन के कागजात देते हुए देवीलाल

चलती सरकार से सर्वथा अलग जनता की अपनी सरकार है। हमने कांग्रेसी तानाशाही को तिलांजलि दे जनता की जवाबदेही वाली सरकार स्थापित करने का प्रयास किया है। सख्ती के स्थान पर हम प्रेम से काम करा रहे हैं, इसलिए भ्रमवश लोग इसे प्रशासनिक ढिलाई का नाम दे रहे हैं। हमारी सरकार बेरोकटोक चल रही है। आज कोई छोटा-से-छोटा आदमी भी बड़े से बड़े अफसर के पास बेधड़क अपनी फरियाद पहुंचा सकता है।" इस धुन में हरेक कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वह रोज पेड़ के नीचे एक घंटा जनता दरबार लगाये।

ढील की वजह: प्रशासन में ढील का मुख्य कारण मुख्यमंत्री का पर्यटन-प्रेम बताया जाता है। राजधानी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के एक कर्मचारी ने बताया कि महीने के २० दिन उसे देवीलाल के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। दौरे पर रहने का देवीलाल का शौक पुराना है। हरियाणा की अप्रत्याशित, आशातीत विजय के पश्चात राष्ट्रीय विपक्ष के हीरो बनने की उनकी ललक ने इसे और बढ़ाया है। आमंत्रण-निमंत्रण चाहे हरियाणा के दूरदराज के गांव का हो अथवा देश के किसी सुदूर प्रांत का, देवीलाल झट हाजिर हो जाते हैं। रही सही कसर ऐसे मौकों पर जुटे उनके लग्गू-भग्गू यह कह कर पूरी कर देते हैं कि उनमें राष्ट्रीय नेता बनने की पूरी कूवत है। और यह उनके अगले दौरे और विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास का पर्याप्त चारा होता है। उन्हें इस बात की कतई फिक्र नहीं कि अगर वह इसी तरह भ्रमण करते रहे, तो उनकी सरकार लंगड़ाती रहेगी।

हरियाणा विशेषकर राजधानी चंडीगढ़ में उनकी गैरहाजिरी का लाभ जो अनेक लोग उठाते हैं, उनमें उनके दो बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह सर्वोपरि बताये जाते हैं। बड़े बेटे ओम प्रकाश संगठन पर काबिज हो गये। छोटे ने प्रशासन की नकेल अपने हाथ में ले ली। दोनों के बीच अधिकाधिक सत्ता हथियाने की होड़-सी लग गयी जो समय से पहले एक उत्तराधिकार-युद्ध में परिवर्तित हो गयी। फलस्वरूप प्रशासन में हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और गुटबंदी के आरोपों का बोलबाला हो गयो। हरियाणा में तो इस सबकी चर्चा गुपचुप ही हुई, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर इसने भीषण स्वरूप धारण कर लिया।

राष्ट्रीय विपक्ष इस सबसे चिंतित और व्यग्र हो उठा। देवीलाल का इस ओर ध्यानाकर्षित कर सावधान करना उसने मुनासिब समझा। तब जाकर कहीं उनके कान पर जूं रेंगी। देवीलाल के एक करीबी सूत्र के अनुसार घर पर उन्होंने अपने बेटों-बहुओं की एक गुप्त बैठक की। दोनों बेटों से अपनी-अपनी हरकतें और दखलंदाजियां बंद करने की सलाह दी। जब उन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने आगबबूला हो धमकी दी कि वह स्वयं इस्तीफा दे देंगे। उनकी यह चाल कारगर सिद्ध हुई। बेटों ने न केवल अपनी अपनी कारगुजारियों पर लगाम लगाने का वायदा किया, बल्कि बाद में अपने-अपने पदों से इस्तीफे भी दिये।

घटनाक्रम ने तब एक नया मोड़ लिया, जब मुख्यमंत्री के दोनों बेटों ओम प्रकाश और रणजीत सिह के इस्तीफे के बाद पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों का मत है कि मंत्रियों ने अपने-अपने सरपरस्त मुख्यमंत्री-सपूतों के इस्तीफे के बाद उनसे वफादारी जताने के लिए यह कदम उठाया। किंतु जानकार लोगों का कहना है कि स्वयं देवीलाल ने इस मौके का लाभ उठाते हुए अपने मंत्रिमंडल में वांछित फेरबदल करने की ठानी और सार्वजनिक इस्तीफे की तुरंत मांग पेश कर दी।

इस्तीफा प्रकरण में भी देवीलाल की अनूठी कार्य-शैली उजागर हुई। सबके इस्तीफे जेब में रख वह एक सप्ताह के लिए देश भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान राज्य में अनिश्चितता का माहौल बना रहा और प्रशासन लगभग ठप रहा। इस बीच अटकलों-अफवाहों का बाजार अवश्य गर्म रहा। खासकर यह चर्चा जोर पकड़ गयी कि पूर्व उद्योगमंत्री संपत सिह, जिनके ऊपर ओम प्रकाश चौटाला के साथ दिल्ली के कालोनाइजरों से करोड़ों रुपए बटोरने के आरोप थे, की छुट्टी होने वाली है।

मुख्यमंत्री की वापसी पर ये अटकलबाजियां तब गलत साबित हुईं, जब संपत सिह का पत्ता कटने की जगह उन्हें गृहमंत्री बना दिया गया। पुनर्गठित मंत्रिमंडल में भी कोई खास रद्दोबदल नहीं किया गया। पुराने मोहरों की केवल अदलाबदली हुई। इस्तीफा देने के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला का दबदबा बढ़ा नहीं, तो कम भी नहीं हुआ। हां, यह अवश्य है कि रणजीतसिह का कद कुछ कम हुआ प्रतीत होता है। किंतु देवीलाल को अपनी हथेली समान जानने वाले लोकदल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, "यह मात्र देवीलाल की एक सोची-समझी चाल है। जाहिर है कि पानी से खून अधिक गाढ़ा होता है। इसके चलते वह अपने बेटों से संबंध विच्छेद तो कर नहीं सकते, किंतु अपनी बेदाग छवि बनाये रखने के लिये उन्होंने लगाम अपने हाथ में ले ली है। इतना ही नहीं उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने मंत्रिमंडल को इस ढंग से छोटा किया है कि विभिन्न घटकों में किसी तरह की बदमजगी पैदा न हो और न ही असंतोष पनपे।"

चौटाला की संगठन-शक्ति और राजनीतिक सूझ-बूझ की प्रशंसा स्वयं देवीलाल ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे के बाद भी की है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि रणजीत को निष्प्रभावी करना चाहते हैं। हाल में उनके गुट के नेता रण सिह मान की पुनः नियुक्ति कर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। एक अन्य जानकार सूत्र ने बताया कि देवीलाल ने बेटों की रस्साकशी को बड़े दूरंदेशी से निपटाया है। वह बेटों की छाया से उबर नहीं सके हैं, किंतु राष्ट्रीय परिदृश्य को मद्देनजर रख कर और विपक्ष की साख बनाये रखने के लिए उन्होंने अपने बेटों को फिलहाल हाशिये पर रख दिया है।

कांग्रेस के बुजुर्ग नेता एवं महासचिव नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने 'माया' से हुई लंबी बातचीत के दौरान दावा किया, "हरियाणा का इस्तीफा [illegible]

ओमप्रकाश चौटाला

रणजीत सिंह

हरियाणा विशेषकर राजधानी चंडीगढ़ में उनकी गैरहाजिरी का लाभ जो अनेक लोग उठाते हैं, उनमें उनके दो बेटे ओमप्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह सर्वोपरि बताये जाते हैं। बड़े बेटे ओमप्रकाश संगठन पर काबिज हो गये। छोटे ने प्रशासन की नकेल अपने हाथ में ले ली। दोनों के बीच अधिकाधिक सत्ता हथियाने की होड़-सी लग गयी जो समय से पहले एक उत्तराधिकार-युद्ध में परिवर्तित हो गयी। फलस्वरूप प्रशासन में हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और गुटबंदी के आरोपों का बोलबाला हो गया।

देवीलाल का एक नाटक मात्र है। इससे उन्होंने अपने पारिवारिक झगड़े को सार्वजनिक रूप दे दिया, साथ ही भ्रष्टाचार के मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भी बंटाया है।"

काला कारनामा: कांग्रेसियों के अनुसार सूखा राहत के तहत ओम प्रकाश द्वारा जमा की गयी भारी धनराशि का कोई हिसाब-किताब नहीं है। अतः वे इसे देवीलाल सरकार की नाक के नीचे किया गया एक काला कारनामा करार देते हैं। साथ ही हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण (हुटडा) में कालोनाइजरों से वसूली करोड़ों की संपत्ति में वह ओम प्रकाश और पूर्वउद्योग और शहरी विकास मंत्री संपत सिंह को कठघरे में खड़ा करते हैं। कहा जाता है कि दोनों ने साठगांठ कर इन कालोनाइजरों को कम विकास शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान की। बदले में करोड़ों की काली कमाई की। जब मामला प्रेस के जरिए उछला, तो देवीलाल ने निलंबन के आदेश सहित सजा केवल दो आई०ए०एस० अधिकारियों को दी और विकास शुल्क बढ़ाकर ३ करोड़ ७२ लाख रुपए प्रति एकड़ कर दी।

इस मामले में बेदाग छूटे गृहमंत्री संपत सिह का दावा है, "यदि कोई यह साबित कर दे कि मैंने पांच पैसे भी किसी से गलत तरीके से लिये हैं, तो मैं केवल पद से ही नहीं राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा।" अपनी सफाई में वह कहते हैं, "मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप इसलिए लगे, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था। पूर्व सरकार द्वारा विशेष कोटे के तहत अनगिनत प्लाट बताशों की तरह बांटे गये थे जिन्हें मैंने रद्द कर दिया था। प्लाट पाने वालों में अनेक पत्रकार, न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जाहिर है कि निहित स्वार्थों पर की गयी इस चोट से तिलमिलाकर उलटा मुझ पर इलजाम लगाया गया।" स्वयं मुख्यमंत्री भी उनके दावे के कायल हुए प्रतीत होते हैं। तभी उन्हें पदोन्नत करके गृहमंत्री बना दिया है।

भ्रष्टाचार के इस होहल्ले को मुख्यमंत्री देवीलाल कांग्रेस का कुप्रचार मानते हुए कहते हैं, "सूप बोले-तो-बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें बहत्तर छेद। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कांग्रेसियों को अपनी ही प्रेत छाया चारों ओर दिखाई दे रही है। हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से खतम करने का कड़ा प्रबंध किया है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं-चाहे छोटा हो या बड़ा। इसके लिए हमने भ्रष्टाचार विरोध आयोग बनाया है जिसका अपना फौरी कार्रवाई दस्ता है।"

भ्रष्टाचार कम हुआ है, इसके दावे में संपत सिह कहते हैं कि हमने राजस्व और कर-चोरी को रोक कर गत वर्ष की वसूली ३०६ करोड़ से बढ़ाकर ३६७ करोड़ कर दी है।

भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में हरियाणा सरकार के फंसने का मूल कारण यह बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े अनेकानेक लोग किसी-न-किसी लाभप्रद पद पर आसीन हैं। देवीलाल के बेटों के अलावा उनके भांजे डा० कमलवीर सिंह प्रशासन पर पूरी तरह हावी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री की हाजिरी गैरहाजिरी में वही सरकारी काम-काज देखते हैं, जिसकी उनको कतई समझ नहीं। उनके अनेक दलाल बताये जाते हैं और हर काम का बंधा दाम। इनके निंदक इन्हें चुगल सम्राट पुकारते हैं। देवीलाल के बेटों में लड़ाई लगाने में इनकी अहम भूमिका कही जाती है।

लोकदल के पूर्व सांसद और उपाध्यक्ष रामेश्वर सिंह का कहना है, "देवीलाल ने पूरे राज्य को घर की खेती बना दिया है। उनके नजदीकी नाते-रिश्ते के लोग कमाई के पदों पर अजगर की तरह पसरे हुए हैं। यदि ये दूध के धुले होते, तो देवीलाल इतने घोटालों-कुप्रचारों के बाद जांच आयोग न बैठाते? देवीलाल ने पिछले छह-सात महीनों में जो लूटखसोट होने दी है, उससे लगता है कि उन्हें इसका पूरा भरोसा नहीं कि उनकी सरकार बहुत दिनों चलेगी। अभी तक उन्होंने कोई लोक कल्याणकारी काम भी नहीं किया है।".

सिह के अन्य आरोपों में चाहे जो भी सचाई हो, पर उनकी अंतिम बात सही नहीं है। सत्तारूढ़ होने के साथ ही देवीलाल सरकार ने जन कल्याण और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। कांग्रेस की पिछली सरकारों की तुलना में उन्होंने शहर से अधिक गांव और कृषि-क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान की है। चुनावी वायदों के तहत देवीलाल ने जो दो कार्यक्रम लागू किये, वे हैं, वृद्धावस्था पेंशन व कर्ज माफी। ६ लाख ७० हजार बूढ़ों को सरकारी खजाने से १०० रुपए मासिक पेंशन बांध दी गयी है। मुख्यमंत्री के अनुसार निष्प्रयोजन, अवसादमय जीवन जीने वाले जिन वृद्धों को पहले घर में बोझ समझा जाता था, आज उनकी पारिवारिक हैसियत पेंशन से बहाल हो गयी है। इसकी पुष्टि करते हुए करनाल से आयी लोकदल की एक समर्थक रामकली ने बताया, "मेरे गांव के सत्तर वर्षीय गिरधारी सिंह की जो खाट पहले गोशालें में बिछायी जाती थी, अब फिर वापस दालान में पहुंच गयी है।"

इसके विपरीत कांग्रेसियों का दावा है कि पेंशन देने में पहल देवीलाल सरकार ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने ही की थी। फर्क केवल इतना था कि वह १०० की जगह ६० रुपए देती थी, किंतु उनकी पेंशन ६० वर्ष और उसके बाद के बूढ़ों को मिलती थी जबकि देवीलाल ने पेंशन की आयु सीमा बढ़ाकर ६५ वर्ष कर दी है।

कांग्रेस के इस दावे का खोखलापन इसी से जाहिर है कि पहले कुल ४० हजार बूढ़ों को यह पेंशन मिलती थी। इनमें से कितनों को असल में और कितनों को महज कागज पर पेंशन मिलती थी, इस बारे में लोकदल वाले ही नहीं, अधिकारियों को भी संदेह है। कांग्रेस-शासन काल में पेंशन के लिए रिश्वत और रसूख का सहारा लेने के बाद ही जाकर किसी भाग्यवान बूढ़े को यह सहूलियत प्राप्त थी। इतने पर भी उसे पेंशन लेने खुद जाना और अपने

संपत सिंह

यदि कोई यह साबित कर दे कि मैंने पांच पैसे भी किसी से गलत तरीके से लिये हैं, तो मैं केवल पद से ही नहीं राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा।

कृपाराम पूनिया

हमारी सरकार बंसीलाल की तरह लाठी के बल पर और भजनलाल की भ्रष्टाचार के बलबूते चलती सरकार से सर्वथा अलग जनता की अपनी सरकार है।

जीवित होने का दावा पेश करना पड़ता था।

आज स्थिति दूसरी है। राज्य के तमाम बूढ़ों को भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मासिक पेंशन मनीआर्डर द्वारा भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया में नौकरशाही का शिकंजा कहीं आड़े नहीं आता। यह सारा काम कंप्यूटरों के जरिए अति सहजतापूर्वक किया जा रहा है।

देवीलाल का कर्जमाफी का मुद्दा विवादों से रहित नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस सहित कुछ लोग जहां इसे पूरा 'फ्राड' करार दे रहे हैं, वहीं दूसरे इसे राज्य को दिवालिया बना देने वाला एक अविवेकपूर्ण कदम ठहरा रहे हैं। नरेश चन्द्र चतुर्वेदी के अनुसार, "देवीलाल ने चुनाव के समय साढ़े १३०० करोड़ रुपए कर्ज माफी का वायदा किया था। घटाते-घटाते २६६ करोड़ पर आ गये। इसमें से भी १६५ करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों का है जो तब तक माफ नहीं हो सकता, जब तक या तो कर्जदार या स्वयं हरियाणा सरकार उसे चुकता न करे। सहकारी बैंकों के करीब ५०-६० करोड़ रुपए के कर्ज ही माफ किये गये हैं। शेष कर्जों की नाटिसें बराबर किसानों के पास पहुंच रही हैं जिससे उनमें व्यापक असंतोष फैलता जा रहा है।"

यह जन असंतोष कांग्रेसियों को भले ही दिखायी दे रहा हो, किंतु हरियाणा की बहुसंख्यक किसान जनता आज देवीलाल की तारीफ करते नहीं थकती। कारण लोकदल-भाजपा की साझा सरकार ने पहली वार कृषि-क्षेत्र और गांवों को अपने शासन का मूलाधार बनाया है। अकाल की भयंकर छाया से बचने के लिए ट्यूबवैलों की व्यवस्था करने के साथ-साथ पहली बार सिंचाई के लिए रोजाना लगातार आठ घंटे तक बिजली सप्लाई की मक्की व्यवस्था की है। कांग्रेस समर्थक भी यह स्वीकारते हैं कि बिजली सप्लाई शुरू होने और समाप्त होने से आप रोजाना अपनी घड़ी मिला सकते हैं।

कुल उत्पादित बिजली का ६० प्रतिशत कृषि-क्षेत्र के लिए तय कर दिया गया है जो भारत में सर्वाधिक है। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ उसकी चोरी की भी रोकथाम की गयी है। नतीजतन उत्पादित बिजली से कुल चोरी का अंश २४ प्रतिशत से घटकर १८ प्रतिशत हो गया है। इसके फलस्वरूप भिवानी, महेन्द्रगढ़, रोहतक के झज्झर आदि भयंकर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में भी ६५ प्रतिशत कृषि-क्षेत्रों को आज जो सिंचाई सुविधा प्राप्त है, उसी के बलबूते वहां के लोग जिंदा हैं।

कुछ आलोचकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्व देने की कीमत राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को चुकानी पड़ रही है। उद्योग मंत्री कृपाराम पूनिया इससे असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, "यह आरोप गलत है कि हम औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। हमें भलीभांति पता है कि किसी राज्य के विकास की नींव उसका औद्योगिकीकरण है। अतः उसके विकास के लिए हम कई नयी योजनाएं बना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में बिजली की कमी है। इसे पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयासरत हैं।"

दिवालियेपन का आरोप: सरकार के दिवालियेपन के कगार पर खड़े होने का इलजाम लगाते हुए अनेक कांग्रेसी नेता कहते हैं कि देवीलाल ने ठोस आर्थिक कार्यक्रम चलाने की अपेक्षा सस्ती लोकप्रियता का रास्ता अपनाया है। उनके कर्ज माफी और वृद्धावस्था-पेंशन जैसे अनुत्पादक कदमों से राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने की जगह निरतर बिगड़ती ही जायेगी। इन नेताओं की टिप्पणी है, "देवीलाल यथार्थ की धरती छोड़ कर कल्पना के जिस आकाश पर उड़ रहे हैं, उसमें शीघ्र मुंह के बल गिरना अपरिहार्य है।" गत सितंबर-अक्तूबर में जोरदार चर्चा यह थी कि सरकार की अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति भी नहीं रह गयी है। यद्यपि अब सरकार इस स्थिति से उबर गयी है, किंतु लोग सशंकित हैं कि सरकारी खजाना किसी भी दिन खाली हो सकता है।

इन आरोपों को मिथ्या करार देते हुए राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष मूलचंद्र जैन प्रश्न करते हैं, "विरासत में हमें मिला ही क्या? २०० करोड़ का घाटा। वर्षों के रोगी को रातोरात निरोग नहीं बनाया जा सकता। कांग्रेस ने पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। यहां तक कि ५८५ करोड़ का जो योजना कार्यक्रम बनाया गया था, उसके आंकड़े ही गलत थे। ७० करोड़ के बिजली बोर्ड के घाटे का उक्त बजट में उल्लेख नहीं था। साथ ही केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता में ५० करोड़ की अतिरिक्त आय दिखायी गयी थी। हमने स्थिति से निपटने के लिए ९२ करोड़ के अतिरिक्त आय की व्यवस्था की है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य के लिए यह एक अनूठा प्रयास है। इसे विवेकपूर्ण ढंग से लागू करने के कारण जनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में सरकार के दिवालिया होने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

राज्य के लोकदल-भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य की खस्ता वित्तीय दशा के लिए सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। चुनाव पूर्व कर्ज मेले के रूप में दोनों हाथों से पैसा लुटाने वाली केंद सरकार ने नयी हरियाणा सरकार की मदद से हाथ खींच लिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चुनाव पूर्व जो वायदा किया था कि हरियाणा को ४०३ करोड़ रुपए दिये जायेंगे, उसका मिलना तो दूर, चर्चा भी नहीं हो रही है। सूखा राहत के लिए हरियाणा ने ७५० करोड़ की जो फसल-क्षति दिखाई थी, उसके तहत ४६८.३५ करोड़ की मांग की थी। इसके एवज में मात्र ३७ करोड़ साढ़े २२ लाख रुपए दिये गये। वित्त आयोग ने ओवरड्राफ्ट के लिए एक हफ्ते की सीमा बांधकर दोहरी मार की है, जो इसके पहले कभी नहीं हुई थी। किंतु केंद्र की इन चालों से राज्य सरकार बिलकुल हतोत्साहित नहीं, ऐसा राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री का दावा है।

केंद्र की इस उपेक्षा की भरपाई का एक सराहनीय कदम है 'मैचिंग ग्रांट' (समान सहायता) योजना। इसके तहत जनकल्याण के कार्यों में स्थानीय सहायता के बराबर राशि राज्य सरकार प्रदान करती है। मसलन स्कूलों, अस्पतालों, धर्मशालाओं आदि के निर्माण के लिए सरकार और जनता की समान साझेदारी। महिलाओं संबंधी योजनाओं में सरकारी अनुदान दुगना होता है। इस नयी योजना का परिणाम यह होगा कि स्थानीय जनता की अपने विकास एवं कल्याण-कार्यों में शिरकत बढ़ जायेगी, दूसरे सरकारी खर्चे आधे हो जायेंगे।

देवीलाल सरकार के समर्थन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात गिनायी जाती है, वह है सांप्रदायिक सद्भाव। आतंकवाद-हिंसा के शिकार पंजाब से जुड़े होने और नित्य प्रति दर्जनों निरीह लोगों की हत्या किये जाने के बावजूद प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक वारदात होने की जगह हरियाणा में अमन चैन कायम है। सिखों का राज्य से किसी प्रकार पलायन नहीं हुआ है। सिख समुदाय के लोग देवीलाल को

ज़रा सोचिए आपने बिजली जाने से

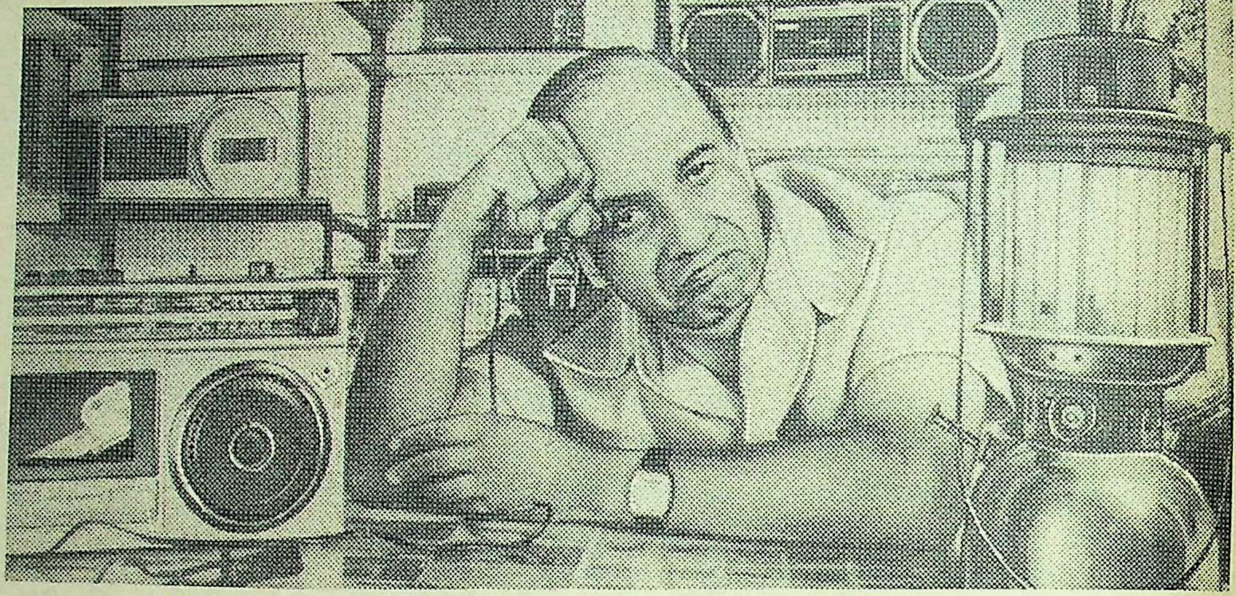

कितने ग्राहक खो दिए!

यह बहुत खराब लेकिन सच बात है कि अंधेरे में कोई खरीददारी नहीं करता। और यह भी सच है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो आपकी बिक्री कैसे होगी। लेकिन बिक्री हो या न हो आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। यानि हर बार जब भी बिजली जाएगी, आपकी जेब कुछ और तंग हो जाएगी। लेकिन यह सब पुरानी बातें हैं।

चूंकि अब आपको रोज़-रोज़ की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का आसान सा समाधान ले आए हैं बिड़ला यामाहा, जिन्होंने भारत में पहली बार बनाए हैं विश्व-स्तर के जेनरेटर। भरोसेमंद और ईंधन बचाने वाले लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर — दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक वाले — जो बिजली बंद होने पर भी आपको देते हैं बिजली। चलाने में एकदम आसान, एक झटके में हो जाएं स्टार्ट!

यही हैं वे एकमात्र पोर्टेबल जेनरेटर जो खासतौर पर भारतीय परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए बने हैं। गरजती बारिश हो या चमकती धूप, जितना जी चाहे बेदर्दी से इस्तेमाल कीजिए, ये चुपचाप चलते रहेंगे। और अगर कभी कुछ खराबी आ भी जाए — जिसका मौका शायद ही कभी आए — तो जापान के यामाहा से खासतौर पर प्रशिक्षित हमारे सर्विस इंजीनियर उसे ठीक कर देंगे — चाहे आप कहीं भी हों — 24 घंटे के भीतर।

इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपको कभी बिजली की कटौती का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इतने सारे उन समझदार लोगों की ही तरह जो अपना लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर खरीद चुके हैं।

अपना लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर आज ही खरीदिए और आज ही से दिन-दूना रात-चौगना मुनाफा कमाइए।

कृपया मुझे भेज दीजिए

☐ मुफ्त सूचना पुस्तिका ☐ आर्डर फार्म

मुझे चाहिए लिटिल जीनी अपने

☐ घर ☐ दफ्तर ☐ वर्कशॉप ☐ शोरूम के लिए

नाम ____________________

व्यवसाय ____________________

पता ____________________

____

35

मार्केटिंग डिवीजन

बिड़ला यामाहा लिमिटेड

ए-7, साउथ एक्स्टेंशन भाग-1, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110 049

बिड़ला यामाहा पोर्टेबल जेनरेटर
खासतौर पर भारतीय परिस्थितियों के लिए बने

Sista's-BYL-241/88 HN A

अपना महान रक्षक समझते हैं।

प्रशासन में मुख्यमंत्री के पारिवारिक हस्तक्षेप के बावजूद लोग सरकार द्वारा नगर पालिका तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को अति सराहनीय कार्य बताते हैं। उल्लेखनीय है कि १९६६ में हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहली बार यह स्थानीय चुनाव कराये गये हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के विरुद्ध तीन बार निंदामूलक प्रस्ताव पास किये थे, किंतु उसने फिर भी ये चुनाव नहीं कराये थे।

यही कारण है कि कांग्रेस के आरोपों के बाण लक्ष्यभेद नहीं कर सके हैं। नयी सरकार के बारे में धुआंधार कुप्रचार के बावजूद प्रभाव पढ़ी-लिखी शहरी जनता पर थोड़ा बहुत भले ही पड़ा हो, किंतु राज्य की आम जनता की निगाह में देवीलाल की बेदाग और गरीब समर्थक छवि अभी भी विद्यमान है। देवीलाल सरकार की कुछ कमियों-खामियों के बावजूद कांग्रेस इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने में पूर्णतया अक्षम है। कारण पार्टी सांगठनिक रूप से लुंजपुंज होने के साथ-साथ राज्य में नेतृत्वविहीन है। कांग्रेस के हरियाणा मामलों के एक जानकार वरिष्ठ नेता के अनुसार गत ६ सितंबर को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया था। उस समय राज्य के दो पार्टी सचिवों को नामज़द किया गया था। शेष पदाधिकारियों की आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। कांग्रेस संगठन आज केवल कागजी रह गया है।

देवीलाल दूध के धुले नहीं : रामेश्वर सिंह

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बलबीर पाल शाह पहली बार विधायक बने हैं, वह कोई जाने-माने नेता या पुराने पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं। उनको बलराम जाखड़ और भजनलाल का वरदहस्त भर प्राप्त है।

कांग्रेस की इन कमजोरियों के चलते देवीलाल की सरकार तब तक संकट में नहीं फंसेगी, जब तक वह अपने लिए खुद कांटे न बोये और इसकी आशंका कम ही प्रतीत होती है। आज हरियाणा पर समूचे राष्ट्रीय विपक्ष की आंखें टिकी हुई हैं। जैसा कि भाजपा नेता व हाल के मंत्रिमंडलीय इस फेरबदल में नागरिक आपूर्ति मंत्री बनी सुषमा स्वराज कहती हैं, "हरियाणा की सरकार केवल हरियाणा की नहीं है। पूरे देश में विपक्षी विकल्प हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर निर्भर है। जनता सरकार के कटु अनुभव को कोई भूला नहीं है। यदि हमारी सरकार यहां असफल हो जाती है, तो जनता हमें दुबारा अपना मत और विश्वास प्रदान नहीं करेगी।"

देवीलाल के फैसले अब हरियाणा की हदें पार करके हिंदी भाषी पड़ोसी राज्य उ०प्र० तक अपना प्रभाव डालने लगे हैं। हरियाणा में गन्ने की बढ़ी वसूली कीमत का हवाला देकर भारतीय किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने पश्चिमी उ०प्र० में जो जबर्दस्त आंदोलन चलाया है, उससे वीर बहादुर सिंह की गद्दी हिल गयी है। हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य का गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करने वाले एक बुजुर्ग पत्रकार की टिप्पणी है कि राज्य की भावी राजनीति पर अमिट छाप छोड़ने वाले देवीलाल के नारे की गूंज राष्ट्रव्यापी होगी। आगामी आम चुनावों में देवीलाल-मुद्दा एक दूरगामी, महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभायेगा।

—रंजना कक्कड़
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

कार्य कुशल
रीटा
सिलाई मशीन
अनेक घरेलू एवं औद्योगिक मॉडल्स में उपलब्ध
IS:1610
ISI
Rita
जीवन पर्यन्त सेवा के लिए निर्मित
adEnvoys

साक्षात्कार/**देवीलाल**

कांग्रेस चोरों की सरकार थी, मेरी जनता की है

७४ वर्ष की अवस्था में यह नहीं लगता कि चौधरी देवी लाल में जूझने की शक्ति कम हो गयी है। जिस तरह पहले वह सत्ता में आने के लिए संघर्षरत थे, उसी तरह आज अपनी सत्ता को जमाने के लिए अपने विरोधियों से जूझ रहे हैं। लंबे और कड़े संघर्ष के बाद दुबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल यह मानते हैं कि उन पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं। उनका दावा है कि राजीव की सत्ता के उखड़ने का क्रम हिंदी-क्षेत्र में हरियाणा से शुरू हो गया है। रंजना कक्कड़ ने चौधरी देवी लाल से विविध मुद्दों पर लंबी बातचीत की है। प्रस्तुत हैं, अंश :

माया: विशाल जनमत के बावजूद आपकी सरकार इतनी जल्दी कठिनाइयों में क्यों घिर गयी, जिसके कारण बचाव मे आपको अनेक सुरक्षात्मक कदम उठाने पड़े?

देवीलाल: हमारी सरकार को कोई कठिनाई नहीं है। बड़ी आसानी से चल रही है, सिवाय इसकें कि जिन विपक्षी पार्टियों का चुनाव में लोगों ने सफाया कर दिया था, अब उनके सामने हरियाणा में अपने को कायम रखने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करें।

माया: कठिनाइयों का प्रमुख कारण भाई भतीजावाद का बोलबाला, चहेतों को प्रश्रय और उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बताया जा रहा है।

देवीलाल: एक कारण तो यह बताया जाता है कि १२८ में से ५० बोर्डों के चेयरमैन देवीलाल के रिश्तेदार हैं। आप यह जानकर हैरान होंगी कि कुल बोर्ड-कार्पोरेशन केवल २७ हैं, इसलिए किस प्रकार हमारे रिश्तेदार ५० बोर्डों के चेयरमैन हो सकते हैं। और २७ में भी ६ आई०ए०एस० अधिकारी हैं। बाकी रह गये २१, इनमें से केवल तीन में ही मेरे रिश्तेदार हैं। एक मेरा दामाद है, दूसरे दामाद के पिता हैं जो स्वयं एम०पी०, एम०एल०ए० रह चुके हैं। इस बार भी वह टिकट के हकदार थे, किंतु उन्हें मैंने टिकट नहीं दिया था। इसलिए मैंने उन्हें बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इन लोगों ने इस्तीफे दे दिये हैं।

माया: क्या आप जिन-जिन को टिकट देने अथवा मंत्रिमंडल में स्थान देने में असमर्थ रहे, उन सबको संतुष्ट करने के लिए आपने बोर्ड के चेयरमैन बना दिये?

देवीलाल: नहीं, उनसे काम लेने के लिए मैंने ऐसा किया था। आखिर वे सभी राजनीतिक कार्यकर्ता ही थे। भाई-भतीजावाद से बचा जाये, इसी के तहत हमने उन्हें टिकट नहीं दिया था। किंतु मेरे रिश्तेदार होने के कारण ही उन्हें पद न दिया जाये यह सही नहीं है। टेकराम हमारे समधी होने के पहले ही एम०पी०,एम०एल०ए० रह चुके हैं।

माया: आपको नाम का मुख्यमंत्री कहा जाता है। शासन बेटों का चलता है और उनके बीच छिड़े उत्तराधिकार-युद्ध ने आपकी पार्टी व सरकार का विभाजन कर दिया है।

देवीलाल: नाम ही नहीं मेरा राज्य भी चलता है। मैं वह आदमी हूं जो गोपीचंद भार्गव के वक्त भी राज्य चलाता था। कोई भी मेरे इशारे के बिना हिल नहीं सकता था। बंसीलाल भी मेरा लाया हुआ था। भजनलाल भी मेरा बनाया हुआ था। ऐसा आदमी जोकि बाहर रहकर भी राज्य चलाता रहा हो, उसको बाहर वाला कोई नहीं चला सकता।

माया: हरियाणा के इस्तीफा-प्रकरण को कांग्रेस मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का मात्र भोंडा नाटक करार दे रही है। इस्तीफा लेने और फेरबदल के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, क्योंकि सामान्यतः कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ और न ही कथित अपराधियों को कोई सजा दी गयी है।

देवीलाल: मेरे खिलाफ केवल उन लोगों ने ही इलजाम लगाये हैं, जिन्होंने चुनावों में बुरी तरह मुंह की खायी है। ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मूल मुद्दा तो कोई था ही नहीं। रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो मेरे खिलाफ, मेरे बेटों के खिलाफ, मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ लगाये गये आरोपों में कोई सचाई नहीं है।

माया: फिर पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेने और फेरबदल करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था?

देवीलाल: मेरा उद्देश्य यही था कि चुनाव के समय मैंने कहा था कि बिजली-पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। उसके साथ मेरा एक और नारा था—'लोकराज लोकलाज से चलता है।' जब विपक्षी लोग झूठा प्रचार कर रहे थे और मैंने प्रेस में देखा कि जनमत कुछ खिलाफ हो रहा है, तो मैंने बैठक करके अखबारों के माध्यम से प्रकट हुए जनमत पर अपने सहयोगियों का ध्यान दिलाया। मंत्रिमंडल के सदस्यों और बोर्ड के सभी चेयरमैनों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर मेरे नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्थन और विश्वास का इजहार किया। ये सभी मेरे वफादार साथी थे और आज भी पूरी तरह मेरे साथ हैं। फेरबदल में मैंने सात मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर किये, बाकी को दुबारा शपथ दिला दिया। जो मंत्रिमंडल से बाहर हैं, उनसे भी काम ले रहा हूं।

माया: इस प्रकरण में यह भी जुड़ गया है कि अपने मंत्रियों के इस्तीफे जेब में रखकर आप भारत भ्रमण को चले गये और बहुत अनिश्चितता का वातावरण छोड़ गये और राजकाज बिलकुल ठप हो गया।

देवीलाल: मेरा कार्यक्रम पहले से तय था। बंगलौर में विपक्षी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था। हैदराबाद में रामाराव ने अपने शासनकाल के ५ साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में बुलाया था। उसके बाद मैं बंबई गया था। ये कार्यक्रम एक महीने पहले से बने हुए थे। मेरे जाने के बाद कोई हलचल हरियाणा में नहीं थी। प्रशासन-कार्य पूर्ववत

सामान्य ढंग से चलता रहा। लोगों ने अफवाहें फैलायीं कि सरकार और प्रशासन में भारी फेरबदल होगा जिसका मैंने अपनी उक्त यात्रा में बयान देकर खंडन किया।

***माया:* जब कोई बड़ा फेरबदल नहीं करना था, तो इसका उद्देश्य क्या था? फिर उन्हीं लोगों को ले लिया आपने।**

देवीलाल: ८ मंत्रियों की मैंने कमी की है। कौन किस योग्य है, इसके आधार पर मैंने विभाग सौंपे हैं। मैंने मंत्रिमंडल को छोटा भी किया है। पहले जहां २३ लोग थे, वही अब १७ लोग हैं।

***माया:* इसका कोई फायदा नहीं हुआ है सरकार को, क्योंकि खर्च कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया है।**

देवीलाल: खर्च कम हुआ है, बढ़ा नहीं।

***माया:* कहा जाता है कि जिनको आप मंत्री नहीं बना सके, उनको चेयरमैन बना दिया है।**

देवीलाल: कांग्रेस के समय से जो चेयरमैन पद चले आ रहे थे, उन्हीं पर नियुक्ति की है, नये नहीं बनाये हैं।

***माया:* क्या इस फेरबदल का उद्देश्य मंत्रियों को उनकी औकात जता देना था?**

देवीलाल: इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि सारे मंत्रियो की मेरे प्रति पूर्ण वफादारी है और वे हतोत्साहित नहीं हैं। पूरी आस्था और विश्वास के साथ मेरे साथ हैं। भले ही वे मंत्रिमंडल में हों या बाहर।

***माया:* इसे आप विडंबना नहीं मानेंगे कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के बलबूते पर आपकी सरकार स्वयं आज उसकी चपेट में है। कारण, एक ओर हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण ने सरकार की इमानदारी पर प्रश्नचिह्न लगाया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नियुक्ति में रिश्वत की चर्चा है।**

देवीलाल: मेरे सामने भ्रष्टाचार का कोई मामला आने पर मैं संबंधित अधिकारी को माकूल जांच के बाद निलंबित कर देता हूं। इसके लिए मैंने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो बनाया है। एक बहुत ईमानदार रिटायर्ड एस०पी० संतोष सिंह के तहत मैंने एक फौरी कार्रवाई दस्ता बनाया है। दस्ता भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत कार्रवाई करता है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करने वाले को मैं चुनौती देता हूं।

***माया:* डी०एल०एफ० कालोनाइजर में एक लाख रुपए की एकड़ का जो कम विकास शुल्क लिया गया, क्या उसकी आपको जानकारी नहीं थी?**

देवीलाल: भजनलाल के समय में नये रिहायशी क्षेत्रों का विकास कर १,४१००० रुपए एकड़ था। जब भजनलाल के बाद बंसीलाल आया, तो उसने इसे बढ़ाकर २,९७००० रुपए कर दिया। इस संबंध में फाइल में जो पृष्ठ थे, उसे गायब कर दिया गया और वह कालोनाइजर्स को दिखाकर उनसे पैसे बटोरने लगा। फाइल का यह भाग उसने नयी सरकार बनने के दो दिन पहले गायब किया था। जब मुझे इस बात का पता चला, तो मैंने उसे तलाश कराया। एक हफ्ते के बाद वह फाइल मिली। मैंने सी०आई०डी० को मामला सौंप दिया और संबंधित सचिव और दो आई०ए०एस अफसरों को निलंबित कर दिया। फिर मैंने बोर्ड का पुनर्गठन किया जिसकी बैठकें हुईं। बोर्ड ने विकास शुल्क ३ लाख ७१ हजार रुपए तय किये। कहां एक लाख ४१ हजार और कहां ३ लाख ७१ हजार। पैसे वसूलने के लिए बंसीलाल ने २ लाख ९७ हजार रुपए शुल्क लगाया था और वह फाइल गुम कर दी थी। इस प्रकार मैंने सरकार को मिलने वाले शुल्क की राशि को कई गुना बढ़ाया फिर भी लोग मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं।

***माया:* भजनलाल का कहना है कि आप अपने बेटों के भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच करायें, तो वह हजारों हलफनामे दायर करा देंगे।**

देवीलाल: यह सरासर बकवास है। हमने उसके खिलाफ अनेक मामले दायर किये हैं किंतु उसने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार यह पहला मामला है जब किसी को जांच कार्रवाई में स्थगन आदेश प्राप्त हुआ हो।

***माया:* चुनावी वायदों पर कहां तक अमल हुआ है?**

देवीलाल: मैंने जो वायदे सार्वजनिक रूप से किये थे, उनमें से एक था किसानों के १५० करोड़ रुपए के कर्जों की माफी। मैंने १५० की जगह २४० करोड़ रुपए के ऐसे कर्जे माफ कराये। भजनलाल आदि बयान देते हैं कि देवीलाल कुछ नहीं कर रहे हैं और उन्हें १२०० करोड़ रुपए कर्ज माफ करना चाहिए। इस १२ सौ करोड़ रुपए में से ७ लाख रुपए तो गत दिनों फतेहाबाद उपचुनाव में जो कांग्रेस उम्मीदवार था, लीला किशन उसके जिम्मे हैं, २७ लाख रुपए करनाल उपचुनाव में खड़े कांग्रेस उम्मीदवार के जिम्मे हैं और भजनलाल के जिम्मे है ५७ लाख रुपए का कर्जा। इस प्रकार साढ़े दस करोड़ रुपए कांग्रेस के पराजित व अन्य उम्मीदवारों पर बाकी हैं। इनकी वसूली के आदेश मैंने दिये हैं। इन्हीं कर्जों को माफ करने की मांग कांग्रेसी कर रहे हैं।

मेरे सामने भ्रष्टाचार का कोई मामला आने पर मैं संबंधित अधिकारी को माकूल जांच के बाद निलंबित कर देता हूं। एक बहुत ईमानदार रिटायर्ड एस०पी० संतोष सिंह के तहत मैंने एक फौरी कार्रवाई दस्ता बनाया है। दस्ता भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत कार्रवाई करता है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करने वाले को मैं चुनौती देता हूं।

मैंने वायदा किया था कि ६५ साल से ऊपर के बूढ़ों को मैं पेंशन दिलाऊंगा। १०० रुपए माहवार पिछले दिनों की पेंशन तो जा चुकी है और तीन महीने की ३०० रुपए अब जा रही है—मनीआर्डर द्वारा। आप किसी गांव में जाकर इसके बारे में खुद पता लगा सकती हैं। मैंने वायदा किया था कि नहर या सड़कों के किनारे के खेतों के पेड़ की आधी मिल्कीयत संबंधित किसान की होगी और आधी सरकार की। मेरी सरकार बनने के बाद नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाने वाले युवाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गयी है—यह भी मेरा एक चुनावी वायदा था।

***माया:* एक और आरोप है कि आपने अपने मंत्रियों सहित अपनी संपत्ति की घोषणा का जो वायदा किया था, वह अभी भी अपूर्ण है।**

देवीलाल: मंत्रियों को मैंने इसके लिए लिखा है। वह भेज रहे हैं।

***माया:* आपके कर्जा माफी के लिए लोग कहते**

हैं, यह प्रचार अधिक है असलियत कम-मात्र ५०-६० करोड़ रुपए कर्ज माफ हुए हैं।

देवीलाल: २४० करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए हैं। मैं सारे कर्ज माफ करने के पक्ष में हूं किंतु केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक रोड़े अटका रहा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि कर्ज वसूली की २० साला किश्त बांध दी जाये—राज्य सरकार स्वयं उसे अदा करेगी। पर रिजर्व बैंक और केन्द्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसी प्रकार किसानों को राहत के लिए मैंने गन्ने की कीमत ३२ रुपए क्विंटल तय की है, जबकि उ०प्र० में यह २८ रुपए, पंजाब में ३० रुपए व राजस्थान में २७ रुपए मात्र है।

माया: यह भी कहा जाता है कि मात्र एक खास किस्म के गन्ने, जिसकी काश्त बहुत सीमित है, की खरीद कीमत आप ३२ रुपए दे रहे हैं, शेष को २८ रुपए ही दे रहे हैं।

देवीलाल: आपको जानकारी नहीं है। जिस गन्ने से अधिकतम रस निकलता है, उसे ३२ रुपए दिया जाता है, किसी खास किस्म को नहीं। इसी के हिसाब से दाम घटता-बढ़ता है। यह विधि हर राज्य में लागू है। किंतु कहीं भी ३२ रुपए क्विंटल नहीं दिया जाता, जितना हमने दिया है।

माया: कर्ज माफी का रिकार्ड आपने कैसे बनाया, जबकि रिजर्व बैंक आपके कथनानुसार सहयोग नहीं कर रहा है?

देवीलाल: सहकारी बैंक के कर्ज हमने माफ किये हैं। जिन गरीब किसानों ने सार्वजनिक क्षेत्र के (सरकारी) बैंकों से भी कर्जे के लिये हैं, उनकी माफी अथवा २० साला किश्त की हमारी मांग सरकार ने ठुकरा दी है। वैसे खुद कांग्रेसी मंत्री चुनाव पूर्व कर्ज मेलों का आयोजन करते रहे हैं। जैसे हरियाणा में गत चुनाव के एक माह पूर्व मई में २९३ करोड़ रुपए के कर्ज कांग्रेस की ओर से बांटे गये थे। यह पूजा, जनार्दन पुजारी खुद कर गया था। इसकी लिस्ट मैंने मांगी थी, जो नहीं मिली। जांच पर पता चला कि ४० फीसदी कर्ज बोगस और बेनामी हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक व केन्द्र सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

माया: वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस ने खुद इसे शुरू किया था और वाहवाही आप लूट रहे हैं?

देवीलाल: पहले बेसहारा लोगों को आवेदन देना पड़ता था, ६० रुपए की पेंशन के लिए। दो-तीन महीने जांच पड़ताल चलती थी। यह पेंशन भी कागजों पर अधिक थी। इसका ब्यौरा भी नहीं है। अब वृद्धावस्था पेंशन अमीर-गरीब सबको मिलती है। पहले बेसहारा पेंशन मुश्किल से दो प्रतिशत लोगों को मिलती थी, वह भी रिश्वतखोरी के बलबूते।

माया: कर्ज माफी और पेंशन के इन लुभावने-लोकप्रिय कार्यक्रमों की कीमत किसको चुकानी पड़ रही है?

देवीलाल: हमने ९२ करोड़ रुपए के करों की व्यवस्था की, जो आज तक कोई कांग्रेसी हुकूमत नहीं कर पायी थी। राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष में सन १९८२ में १८ लाख, १९८३ में १५ लाख, १९८४ में १७ लाख, १९८५ में ७० हजार रुपए और १९८६ में १६ हजार रुपए मिले थे, जबकि इसके तहत अब तक मुझे ४ करोड़ रुपए मिले हैं। यह स्वैच्छिक रूप से मुझे जनता से मिला है और उद्योगपतियों से ड्राफ्ट की शक्ल में। उद्योगपति मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वह उन्हें प्रायः कालाधन देते हैं जैसाकि वह भजनलाल व बंसीलाल को दिया करते थे। पर मैंने वह भ्रष्ट परपरा तोड़ दी और कांग्रेस के मुकाबले सैकड़ों गुना अधिक रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में एकत्रित हो गयी। वह (कांग्रेसी) रुपए खाते थे और मैं बांटता हूं। मैं गांवों में जाता हूं, तो वहां की जनता मुझे धन देती है।

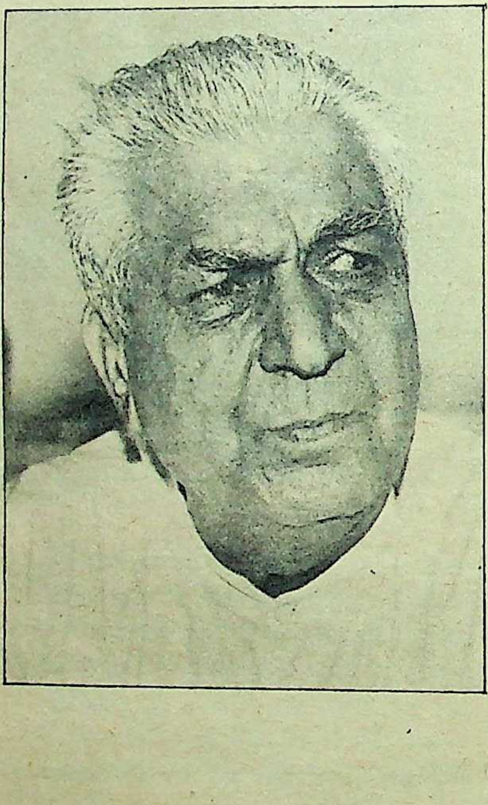

राष्ट्रीय नेता लोग
बनाना चाहते हैं। जनता
जहां बुलाती है, वहां मैं जाता हूं। वैसे
अधिकांश समय मेरा हरियाणा में बीतता है।
मैं किसान को दिल्ली दरबार में शोभित-
स्थापित करना चाहता हूं—खुद
को नहीं।

माया: क्या इन खर्चीले कार्यक्रमों ने राज्य सरकार को दिवालिया नहीं बना दिया?

देवीलाल: मेरी सरकार दिवालिया नहीं है। दिवालिया केन्द्र सरकार बनेगी।

माया: केन्द्र आपके मार्ग में कितनी अड़चनें डाल रहा है और कितनी सहायता कर रहा है?

देवीलाल: केन्द्र ने अकाल सहायता के लिए साढ़े ३६ करोड़ रुपए हरियाणा को देने को कहा था। दिया मात्र १६ करोड़, जबकि राजस्थान को १५३ करोड़ रुपए दिये तथा अन्य कांग्रेस शासित राज्यों को भी भरपूर मदद की। केन्द्र के इस सौतेले व्यवहार के बावजूद हरियाणा के सर्वाधिक अकालग्रस्त इलाके भिवानी, नागनौर, जहां नहरें नहीं हैं, नियमित बिजली सप्लाई होने से आज गेहूं व सरसों की फसलें लहलहा रही हैं।

माया: सरकार को दिवालिया बनने से बचाने के लिए योजना और विकास कार्यों में कटौती और योजनाओं के अमल में देरी की जा रही है, ऐसा विपक्षी कहते हैं?

देवीलाल: यह सही नहीं। हरियाणा की ६०० करोड़ रुपए की योजना है, जबकि पिछली सरकार की ५२५ करोड़ की थी। पुराने परियोजनाओं पर अमल जारी है।

माया: कहा जा रहा है कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र ढीला-नाकारा है। न कोई नीति है न नियम। रोज आदेश बनते हैं और बदले जाते हैं। इसमें नौकरशाही दिग्भ्रमित-दिशाहीन है।

देवीलाल: यह कांग्रेस का दुष्प्रचार है। मेरी नीतियों और आदेश पर काम होता है। जो अधिकारी ऐसा नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नौकरशाही को दिशा देना ही हमारा काम है, जिसमें अभी तक हम सफल हैं।

माया: कहा जाता है कि आपकी प्रशासन में रुचि कम है और पकड़ कमजोर है।

देवीलाल: मेरी प्रशासन में पकड़ जितनी मजबूत है, उतनी न नेहरू की थी, न कैरो की। मैं प्रशासन चलाने में माहिर हूं।

माया: यह भी आरोप है कि राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में राजकाज के लिए आपके पास समय नहीं है और आपकी नजर दिल्ली दरबार पर है।

देवीलाल: राष्ट्रीय नेता लोग बनाना चाहते हैं। जनता जहां बुलाती है, वहां मैं जाता हूं। वैसे अधिकांश समय मेरा हरियाणा में बीतता है। मैं किसान को दिल्ली दरबार में शोभित-स्थापित करना चाहता हूं-खुद को नहीं।

माया: कहा तो यहां तक जाता है कि जून के

अंत तक आप दिल्ली स्थानांतरित हो जायेंगे और हरियाणा में ओमप्रकाश चौटाला की ताजपोशी कर देंगे।

देवीलाल: ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसान का बेटा प्रधानमंत्री हो और हरिजन का बेटा राष्ट्रपति।

***माया:** आरोप है कि आप ने हरियाणा की जो उपेक्षा की है, उससे पार्टी-कार्यकर्ताओं में निराशा व जनता में असंतोष पैदा होने लगा है।*

देवीलाल: जनता में बड़ा संतोष है। कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है और पार्टी संगठित और लामबंद। सरकार बड़ी अच्छी तरह काम कर रही है।

***माया:** भाजपा से आपका तालमेल कैसा है?*

देवीलाल: भाजपा से चुनाव पूर्व जो तालमेल था, वह सरकार और पार्टी दोनों स्तरों पर बरकरार है।

***माया:** कहा जाता है कि यह रिश्ता एकतरफा है और दोस्ती का हाथ भाजपा को ही बढ़ाना पड़ रहा है।*

देवीलाल: मैं उन लोगों को साथ लेकर चल रहा हूं। इसके पूर्व बिरादरी के नाम पर जो छोटे-छोटे नेता पैदा हो गये थे, उनका मैंने आर्थिक कार्यक्रम से सफाया कर दिया है। मैं एक मिसाल देता हूं, भगवत दयाल शर्मा का जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ म०प्र०, उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। वह हरियाणा की जनता से चुनाव पूर्व मेरे समर्थन में वोट देने के लिए कहते थे कि मैं भजन भी कर चुका, बंसी भी बजा चुका पर अब मैं देवी की शरण में आया हूं। अर्थात भजनलाल, बंसीलाल को छोड़ मेरे साथ आ गये हैं। पर चुनाव के तीन दिन पूर्व अर्जुन सिंह व फोतेदार ने आकर उनको समझाया। भगवत दयाल ने बयान दे दिया कि ब्राह्मणों को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। उसने अपने बेटे सहित आठ आदमियों को टिकट दिलवा दिया, पर आठों की जमानतें जब्त हो गयीं। इस तरह अन्य जातियों के आधार पर खड़े उम्मीदवार बुरी तरह हार गये। कारण मैंने आर्थिक कार्यक्रम 'रोटी कपड़ा और मकान' को अपना मुख्य चुनावी नारा बनाया था, जिस पर मैं अमल कर रहा हूं।

***माया:** क्या आप अपनी सरकार के अब तक की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं?*

देवीलाल: मैं अपनी सरकार की उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हूं।

***माया:** आपकी सरकार बंसीलाल व भजनलाल की सरकार से कैसे भिन्न है?*

देवीलाल: वह चोरों की सरकार थी। मेरी जनता की सरकार है।

***माया:** क्या विपक्ष आपकी सरकार की मिसाल देकर आपके नारों को बुलंद कर केन्द्र सरकार का मुकाबला कर सकेगा?*

देवीलाल: विपक्ष आने वाले चुनावों में एक होगा। यह एकता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हरियाणा में पहले दस की दसों संसदीय सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। हमने विधानसभा की ६० सीटें जीतीं। अगली बार दसों संसदीय सीटें हम जीत लेंगे। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं कि रहीम खान और दलबीर सिंह की मृत्यु से खाली हुई संसदीय सीटों का उपचुनाव कराये। उसकी यही हालत शेष देश में होगी। कांग्रेस सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। हमारी सरकार की उपलब्धि का समूचे देश पर असर पड़ रहा है और पड़ेगा। मसलन किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है। उ०प्र० में लाखों किसान हमारे कार्यों से प्रेरणा ले आंदोलन चला रहे हैं। हम १२ मार्च को एक विशाल किसान रैली करने जा रहे हैं जिसमें जनमोर्चा, भाजपा, श्वेतकारी व लोकदल सब भाग लेंगे।

***माया:** राष्ट्रीय विपक्षी एकता में आप अपने को अलग क्यों रख रहे हैं?*

देवीलाल: मैं अपने को अलग नहीं रख रहा हूं। विपक्षी एकता तभी हो सकती है जब विपक्षी पार्टियां एक हों। जोड़-तोड़ से नहीं। मैं तो मजाक में कहता हूं कि विपक्षी पार्टी तो दो ही हैं—एक अकाली दल, दूसरा लोकदल। बाकी जोड़-तोड़ की पार्टियां हैं। **—रंजना कक्कड़**

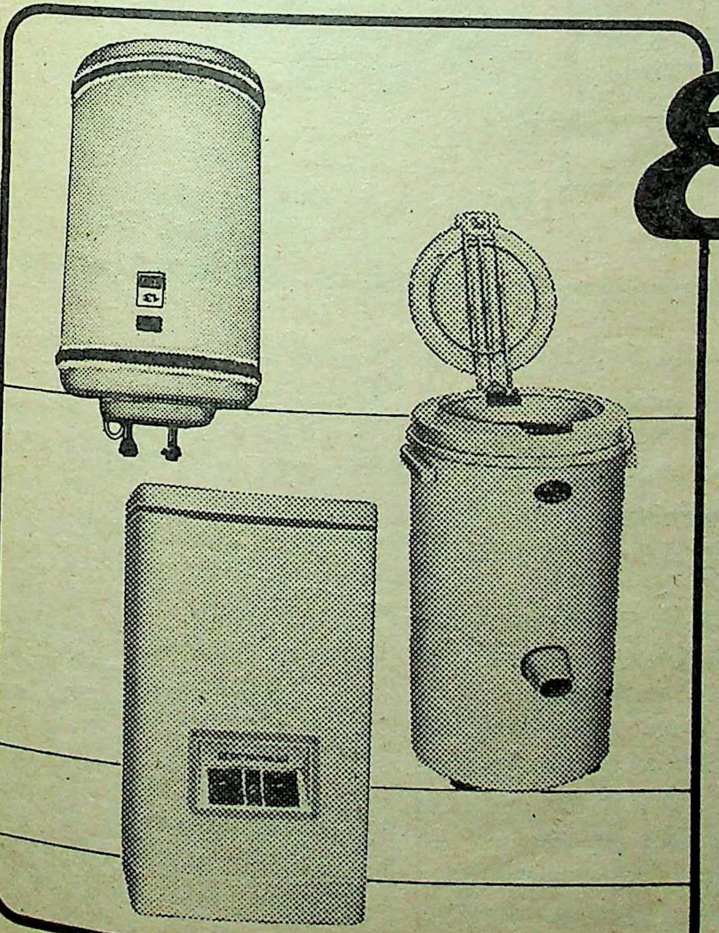

Elite

उत्तमता,
सुंदरता और
बचत के लिए

इलाइट 25 वर्षों से घर-घर में लोकप्रिय नाम। इलाइट द्वारा बनाये बिजली के उपकरण इतने टिकाऊ हैं कि आप वर्षों तक इन पर भरोसा कर सकते हैं।
कड़ी देखरेख में निर्मित इलाइट के उपकरण अपनी कार्यकुशलता और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध हैं।
आकर्षक डिजाइनों और कई मॉडलों में उपलब्ध ये उपकरण सुंदर भी हैं और किफायती भी। साथ ही ये आपको रोजमर्रा के कठिन घरेलू कामों से भी राहत पहुंचाते हैं।

इलाइट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज
5332, चंद्रावल रोड, सब्जीमंडी, दिल्ली-110007

Ishthaar

मेसर्स होमलाइट इलेक्ट्रिकल्स

साक्षात्कार/सिद्धार्थ शंकर रे

निन्यानबे प्रतिशत लोग खालिस्तान विरोधी हैं

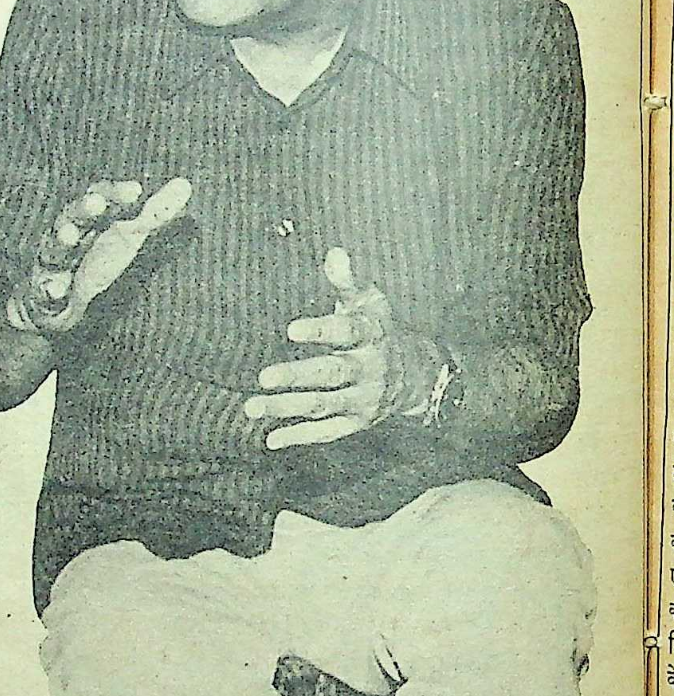

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को बड़ी उम्मीदों के साथ समस्याग्रस्त पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था। कारण प० बंगाल में उनका रिकार्ड नक्सली आंदोलन को सफलतापूर्वक कुचलने की दृष्टि से एक यादगार कारनामा बन चुका था। पंजाब के उनके शुरुआती शांत दिन सहसा बढ़े आतंकवादी हत्याकांडों से गहमागहमी से परिपूर्ण हो उठे थे। अंततः उनकी रिपोर्ट पर ही राज्य में बरनाला सरकार को बर्खास्त कर केन्द्र ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। शुरू में रे और रिबेरो की जोड़ी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि लगा कि आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लग गयी है। किंतु विडंबना यह रही है कि जब-जब रे ने इस संबंध में पूर्ण नियंत्रण की आशा और संभावना प्रकट की, तब-तब आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार और तेज करके उनको गलत साबित कर दिया। राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिज्ञों की आशाओं पर पानी फेरने में कुछ कम भूमिका नहीं निभायी। चर्चा यहां तक चली कि राजनीतिज्ञों ने एक ओर जहां प्रशासन का साथ देने में उत्साह नहीं दिखाया, वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी की। विडंबना यह है कि अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल को एक दूसरे लोंगोवाल की तरह सोचकर पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाने की जिस मंशा से हिरासत से मुक्त किया था, वह सरासर मिथ्या साबित हुआ। पंजाब के नये बदलते राजनीतिक माहौल की गंभीरता इसी से आंकी जा सकती है कि समूचे पंजाब को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। रे के अनुसार पंजाब की समस्या केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मात्र नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक जटिल है। राज्यपाल के रूप में बैरिस्टर रे केन्द्र से पंजाब की वकालत में जुटे हुए हैं। इनमें उन्हें कितनी सफलता प्राप्त होगी यह तो समय ही बतायेगा। प्रस्तुत हैं, उनसे पंजाब की स्थिति पर 'माया' संवाददाता रंजना कक्कड़ की बातचीत के मुख्य अंश:

माया: पंजाब के हत्याकांडों में हाल में हुई वृद्धि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जबकि अनेक आतंकवादी टोलियों के सफाये का दावा किया गया था?

रे: राज्य में ११ मई '८७ को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद प्रशासन को दो प्रकार के आतंकवाद का सामना करना पड़ा— एक कट्टरपंथी आतंकवाद। यह लोगों से एक विशेष प्रकार का जीवन बिताने, खास किस्म के कपड़े पहनने को कहता था। इससे बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए— खासकर सिख। मैं सिखों और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं करता। वे सब पंजाबी हैं। किंतु संयोगवश अधिकांश गोश्त की दुकानें, ८० प्रतिशत शराब की दुकानें और १०० प्रतिशत सिगरेट की दुकानें एक विशेष संप्रदाय के लोगों की हैं। किंतु इसकी चपेट में सभी आये। कट्टरपंथियों की अवज्ञा करने वाले मौत के घाट उतार दिये गये। यह आतंकवाद का एक तरीका था। दूसरा सामान्य आतंकवाद था जो अभी भी मौजूद है। कट्टरपंथी आतंकवाद पर राष्ट्रपति शासन के शुरुआती तीन हफ्तों में काबू पा लिया गया। अब कट्टरपंथी आतंकवाद नहीं रह गया है। किंतु दूसरे प्रकार के आतंकवाद के संबंध में हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। पहले आतंकवादी मारकाट करते और पुलिस जवाबी कार्रवाई करती। नयी नीति के तहत हमने इसे बदल दिया और पुलिस से पहलकदमी करने को कहा। पुलिस उनके गुप्त अड्डों में गयी, शरणदाताओं के घरों पर छापे डाले और इन सब के परिणामस्वरूप आतंकवादियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। आपको आंकड़ों की जानकारी होगी। राष्ट्रपति शासन के बाद गिरफ्तार हुए और मारे गये खतरनाक आतंकवादियों की तादाद पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ा और वह आतंकवादियों के ऐन गढ़ों में घुसकर उनसे लोहा लेने गयी। इससे आतंकवादियों की बौखलाहट बढ़ जाना स्वाभाविक है। नतीजतन पुलिसकर्मियों, आतंकवादियों और बेकसूर लोगों की हत्याओं में तेजी आयी। हमें यह नहीं भूलना है कि आज पंजाब में कोई ऐसा नेता नहीं, जिसका उन पांच गुटों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिन्हें बाहर से धन और निर्देश मिलते हैं और जिनका उद्देश्य हत्या करके उत्तेजना, अराजकता फैलाना और जवाबी हिंसा का माहौल बनाना है। किंतु मैं यह भी कहूंगा कि पंजाब और भारत के अन्य भागों के लोगों ने प्रशंसनीय आचरण किया है। लोगों ने कोई जवाबी हिंसक कार्रवाई नहीं की— सिवाय एक-दो घटनाओं के। मसलन लालडू बस हत्याकांड के बाद। किंतु लोगों को जल्द अहसास हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों का मंशा जवाबी हिंसा का मार्ग प्रशस्त करना है जो उनके लिए अत्यधिक सहायक है। इसलिए जहां तक हत्याओं का सवाल है, उन्होंने

(आतंकवादियों ने) अनुभव किया है कि और बहुतेरे आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये हैं।

मायाः आतंकवादियों को कौन शरण दे रहा है? क्या आप समझते हैं कि आतंकवादियों व राजनीतिज्ञों में साठगांठ है?

रे: मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब के आये दिन के अपने दौरों पर मैं सैकड़ों, हजारों लोगों को देखता हूं और मैं समझता हूं कि हरेक, जिनमें तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, मेरी इस धारणा से सहमत होगा कि पंजाब के ९९ प्रतिशत लोग आज खालिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हैं। वे इनका समर्थन नहीं करते। जब मैं यहां अप्रैल '८६ में राज्यपाल बनकर आया, तो चंद स्थानों पर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की गयी। उस समय विश्वास का अभाव था और कुछ लोग राज्य के बाहर बसने जा रहे थे, किंतु पंजाब में आज वैसी स्थिति नहीं है। इन आतंकवादियों द्वारा आज हिंदुओं की अपेक्षा सिख कहीं ज्यादा मारे जा रहे हैं। ये आतंकवादी न तो पंथ के समर्थक हैं न गुरुनानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु राम दास के। ग्रंथ साहिब में भी उनकी आस्था नहीं है। वे अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं। आज आतंकवाद अपने बेहद घिनौने रूप में उजागर है। पैसे के लिए आतंकवादी तरीके की हत्याएं की जा रही हैं। हत्या का ठेका यह कहकर दिया जाता है, 'तुम मेरे दुश्मन का सफाया कर दो, मैं इतने रुपए दूंगा।' इसलिए वे धन लेकर हत्या करते हैं। दूसरी तरह का आतंकवाद है विभिन्न टोलियों का अंतर्संघर्ष। आप रोजाना मारे गये लोगों का महज नाम ही देख पाते हैं, किंतु उनकी पृष्ठभूमि की यदि आपको जानकारी हो, तो पता लगेगा कि वे एक-दूसरे की हत्या कर रहे हैं। संघर्ष का कारण कभी-कभी धन का उचित बंटवारा न होना या क्षेत्र विभाजन का मसला होता है। इन विवादों के चलते वे एक दूसरे का काम तमाम करते हैं। गुटीय अंतर्संघर्ष का एक अन्य रोचक प्रकार है। मसलन अगर चार या पांच आतंकवादी किसी शरणदाता के घर एक या दो रात बिताते हैं और बाद में उनमें से दो या तीन पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाते हैं अथवा मुठभेड़ में मारे जाते हैं, तो बचे हुए आतंकवादी समझते हैं कि शरणदाता ने पुलिस को खबर दे दी थी। इसलिए वे शरणदाता के पूरे परिवार को जाकर मौत के घाट उतार देते हैं। हाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तीसरी प्रकार की हत्याएं मामूली चोरी-डकैती से संबंधित होती हैं। आतंकवाद पैसा दिलाता है। पहले प्रकार की हत्या भी धन के लिए की जाती है, किंतु उसके ठेके से मिली रकम बड़ी होती है। तीसरे प्रकार की हत्या धन पाने के लिए की जाती है और मुमकिन है कि मात्र एक हजार रुपए ही हाथ आयें और रकम बाद में मिल सकती है, पर पहले हत्या करनी होगी। चौथे प्रकार की हत्या तब की जाती है, जब आपकी किसी के खिलाफ द्वेष-दुर्भावना हो। स्कूल-कालेज के किसी शिक्षक ने आपको फेल कर दिया हो या आपको दाखिला न दिया हो— किसी फर्म या कंपनी के सदस्य से आपको बैर हो और आप उनकी हत्या कर दें।

मायाः क्या आतंकवादियों-राजनीतिज्ञों में मिलीभगत है?

रे: हां ऐसा है। किंतु मैं कोई ब्यौरा नहीं दे सकता।

मायाः यदि ऐसा है, तो इसके खातमे के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

रे: सरकार स्थिति का सावधानी से निरीक्षण कर रही है। मैं इस बारे में भी कोई विवरण नहीं दे सकता।

मायाः क्या आपकी राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की रोकथाम की कोई योजना है?

रे: जहां तक पंजाब की जनता का संबंध है, यह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। अनेक मसले हैं, जिनमें एक अहम है मनोवैज्ञानिक समस्या। इसलिए हमें कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याओं को भी हल करना है। हमें आर्थिक और अंततः राजनीतिक समस्याओं को भी हल करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब की समस्याओं का अंतिम समाधान व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव होगा। आप उसे खंडों एवं अंशों में प्राप्त नहीं कर सकते।

मायाः क्या उसकी प्राप्ति का कोई प्रयास किया जा रहा है?

> सिखों के बारे में दुर्भाग्य से पूर्णतया गलत धारणा फैलायी गयी है। वे उतने ही देशभक्त हैं, जितने भारत के अन्य समुदाय। मेरा विरोध इस बात से है कि जब कभी कोई आतंकवादी हमला करता है, तो समाचारपत्रों में सुर्खी होती है कि सिख आतंकवादी ने इतने लोगों की हत्या की। कोई सिख आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी महज आतंकवादी है। उसका कोई धर्म नहीं। आतंकवादी न तो हिंदू है, न मुसलमान, न सिख न ईसाई। इसलिए यह कहना गलत है कि सिख सहयोग नहीं करते।

रे: हमारा अपना मूल्यांकन है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। हमें समस्या का वैज्ञानिक तरीके से हल करने के लिए दो बातों को जानना जरूरी है। पहला है: हमारा लक्ष्य क्या है? इस बारे में हमने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसी सूरत में कोई खालिस्तान नहीं बन सकता। इस अवधारणा को सबने एक स्वर से ठुकरा दिया है। भारत की एक इंच भूमि भी अलग नहीं की जा सकती। साथ ही, निर्दोष लोगों की हत्या की अवधारणा और आतंकवाद को जीवन का एक तरीका मानना कतई स्वीकार्य नहीं है। जो भी किया जायेगा वह संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही। यदि कोई परिवर्तन का आकांक्षी है, तो उसे संवैधानिक प्रणाली का सहारा लेकर ही आवाज उठाने और अमल कराने की छूट दी जायेगी। ये सब स्पष्ट उद्देश्य हैं। फिर दूसरी चीज है, आपका मूल्यांकन क्या है? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह महज कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है। दूसरे मुद्दे भी हैं, जिनको देखना होगा।

मायाः राज्यपाल के रूप में आपने व्यापक दौरा किया है। लोगों का मनोबल कैसा है?

रे: मैं काफी यात्रा करता हूं। लोग व्यापक रूप में आतंकवाद के पूर्णतया खिलाफ हैं। वे हर तरह से आतंकवाद से लोहा लेना चाहते हैं। खासकर तब, जब देखते हैं कि बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। वे लड़ने को राजी हैं। हमने अमन विकास जत्थे बनाये हैं जिसे 'लोकशक्ति' कहते हैं। यदि आप 'लोकशक्ति' की सभाओं में जायें, तो देखेंगी कि आतंकवाद की भर्त्सना के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं। गत दो महीनों में ग्रामीणों ने स्वयं आतंकवादियों से मोर्चा लिया है।

मायाः क्या लोग पेशकदमी अथवा कोई सुझाव या हल लेकर आते हैं?

रे: हां, मुझे बराबर सुझाव मिलते हैं।

मायाः सिख प्रशासन से सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?

रे: यह धारणा गलत है। मैं सिखों-हिंदुओं में ऐसा भेद नहीं मानता। मेरे लिए वे सब पंजाबी हैं और हमसे सहयोग कर रहे हैं। यदि आप भेद ही करना चाहती हैं, तो मेरा जवाब है कि सिख उतने ही सहयोगी हैं, जितने अन्य। सिखों के बारे में दुर्भाग्य से पूर्णतया गलत धारणा फैलायी गयी है। वे उतने ही देशभक्त हैं, जितने भारत के अन्य समुदाय। मेरा विरोध इस बात से है कि जब कभी कोई आतंकवादी हमला करता है, तो समाचारपत्रों में सुर्खी होती है कि सिख आतंकवादी ने इतने लोगों की हत्या की। कोई सिख आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी महज आतंकवादी है। उसका कोई धर्म नहीं। आतंकवादी न तो हिंदू है, न मुसलमान, न सिख न ईसाई। इसलिए यह कहना गलत है कि सिख सहयोग नहीं करते। सहयोग न करने वाले कुछ अन्य हो सकते हैं। उनका प्रतिशत बहुत कम है और जरूरी नहीं कि वे सिख हों। ऐसे भी मामले हुए हैं, जब हिंदुओं ने शरण दी है।

माया : क्या आपरेशन ब्ल्यू स्टार से अभी भी काफी लोग उत्तेजित हैं ?

रे : हां, चोट और पीड़ा की भावना बरकरार है। हमें इसे मिटाना है और उन्हें समझाना-बुझाना है। यही मनोवैज्ञानिक मसला है, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं।

माया : क्या आप समझते हैं कि अकालियों की एकता राज्य के हित में होगी ?

रे : एकता हर जगह अच्छी होती है, किंतु मैं कह नही सकता कि ऐसा हो सकता है।

माया : बादल और रागी केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं कि वह हत्या के लिए उकसाने, तनाव फैलाने और सिखों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।

रे : मैं किसी राजनीतिज्ञ के साथ राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं चाहता।

माया : पंजाब समझौते पर अमल का क्या हाल है ?

रे : समझौता अभी तक बरकरार है। हमें समझौते के अनुसार कार्य करना है। करार के कई मुद्दे लागू हो गये और कुछ बाकी हैं। उसके संबंध में बने आयोग अध्ययन कर रहे हैं। कुछ फैसले आ गये हैं। उनमें से कुछ पर अमल हो गया, कुछ पर नहीं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैथ्यू आयोग के आदेश के अनुसार अबोहर और फाजिल्का अब पंजाब के हो गये हैं। इस प्रकार कुछ भागों पर अमल हुआ और कुछ पर बाकी है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर देरी की गयी, बल्कि विभिन्न उजागर मुद्दों से देरी हुई है। मैंने देखा है कि राज्यपाल के रूप में जब कभी कुछ प्रमुख मुद्दे मसलन चंडीगढ़ के हस्तांतरण पर अमल के लिए गंभीर प्रयास किये गये, तो हमेशा कोई सामूहिक हत्या या बस-हत्या की बड़ी वारदात की गयीं, जिसमें ३५ से ५० लोग मारे गये। नतीजतन अमल रोक दिया गया। फिर समझौते के विषय में यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रविरोधी आतंकवादी समझौता कभी नहीं चाहते थे। समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद उन्होंने समझौते के जनक संत लोंगोवाल की हत्या कर दी। यदि संत लोंगोवाल की हत्या न होती और वह जीवित होते, तो पंजाब का नक्शा बदला होता। मेरा विश्वास है कि वह समझौता लागू कराते और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाता। किंतु उस चरण में उनकी हत्या करके—जब राज्य में सब कुछ अस्तव्यस्त था—स्थिति बहुत कठोर बना दी गयी। और उन्हें (आतंकवादियों को) पता था कि समझौते की हत्या के लिए उन्हें उसके जनक की पहले हत्या करनी होगी। इस तरह यद्यपि समय लगेगा, पर हमें सुनिश्चित करना है कि करार पर अमल हो।

माया : हाल की रिपोर्टें संकेत करती हैं कि राजनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता को लेकर आप में और बूटा सिंह में मतभेद हैं ?

रे : मैं ऐसी बातें सुन-सुनकर थक गया हूं। ये सब गलत और बेपर की उड़ाने वालों का काम है। न तो बूटा सिंह का मुझसे मतभेद है और न मेरा बूटा सिंह से। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी घृणित अफवाहें क्यों फैलाते हैं ? आज भी हम लोगों में तीन बार बातचीत हुई है।

माया : आप पंजाब की अपनी भूमिका से कहां तक संतुष्ट हैं ?

रे : मुझे तभी संतोष होगा जब पंजाब में शांति का माहौल बन जायेगा। अभी हालात बहुत बुरे हैं और अनेक काम करने बाकी हैं। लोग मुझे बताते हैं कि राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन में दो अच्छी बातें हुई हैं— (१) सांप्रदायिक विभाजन का खतरा समाप्त हो गया है। (२) लोगों का विश्वास लौट आया है। दूसरी ओर राज्य से बाहर गये ५०० परिवार लौट आये हैं। लेकिन हमने जो सोचा था, वह नहीं हुआ। हमें कोशिश जारी रखनी है। कभी हम कामयाब होंगे, कभी नाकाम, किंतु हम कोशिश से बाज नहीं आयेंगे। जब तक आतंकवाद पर भलीभांति नियंत्रण नहीं होता और पंजाब में समुचित शांति कायम नहीं होती, कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। कम-से-कम मुझे तसल्ली नहीं होगी।

माया : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आपने नक्सलवादियों से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। पंजाब का अनुभव कितना भिन्न है ?

रे : नक्सलवादी समस्या बिलकुल दूसरी थी। वह एक कानून-व्यवस्था का प्रश्न था। जिस आर्थिक सिद्धांत का प्रचार नक्सलवादी कर रहे थे, उससे एक भी आदमी सहमत नहीं था। वह मुट्ठी भर लोगों तक सीमित था, जिन्होंने कानून व्यवस्था की बड़ी गंभीर समस्या खड़ी कर दी थी। आपको पता होगा कि उन दिनों रोजाना १०-१५ निर्दोष लोगों की हत्या की जाती थी। किंतु हमने उसे कानून व्यवस्था के समस्या के रूप में निपटाया और पूरे बंगाल ने नक्सलवादियों को कुचलने के हमारे कदमों का समर्थन किया। उस समस्या का कोई अन्य पहलू नहीं था। पंजाब का मसला बिलकुल अलग है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दोनो को एक तराजू पर नहीं तौल सकते।

> राष्ट्रविरोधी आतंकवादी समझौता कभी नहीं चाहते थे। समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद उन्होंने समझौते के जनक संत लोंगोवाल की हत्या कर दी। यदि संत लोंगोवाल की हत्या न होती और वह जीवित होते, तो पंजाब का नक्शा बदला होता। मेरा विश्वास है कि वह समझौता लागू कराते और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाता। किंतु उस चरण में उनकी हत्या करके—जब राज्य में सब कुछ अस्तव्यस्त था—स्थिति बहुत कठोर बना दी गयी

माया : भविष्य के प्रति आप कितने आशावान हैं ?

रे : लोग पंजाब समस्या के समाधान के बहुत इच्छुक हैं। उन्होंने पहले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। लोग आज अमनचैन चाहते हैं और यदि इसकी प्राप्ति के लिए वह और अधिक जुझारू हो जायें, तो शांति स्थापित हो जायेगी। इस रूप में मैं आशावादी हूं। कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में २४ घंटों में से २३ घंटे ५५ मिनट हम निरंतर उत्पादन करते हैं। शेष पांच मिनट में एक जालंधर मे गोलीबारी होती है, एक अमृतसर में। और फिर सारे भारत को केवल इन पांच मिनट के बारे में जानकारी होती है २३ घंटे ५५ मिनट के बारे में नहीं। यदि आप पंजाब जायें, तो पायेंगी कि जीवन चल रहा है। मसलन हमसे कहा गया कि केन्द्रीय पूल में ३० लाख टन चावल देना है। बाकी शेष राज्यों के सूखे के कारण कुल ३७ लाख टन देना था। बहरहाल पंजाब ने ३५ लाख टन से अधिक चावल दिया। शेष राज्यों ने मिलकर भी यदि २५ लाख टन से अधिक दिया हो, तो मुझे आश्चर्य होगा। इस प्रकार उत्पादन जारी है। गत सात महीनों में नौ औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं।

माया : आप अपने वर्तमान जिम्मेदारी पूर्ण काम से कैसे तालमेल बिठा रहे हैं ?

रे : ईश्वर ने मुझे प्रायः ऐसी कठिन स्थितियों में डाला है, जबकि अत्यधिक कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए।

माया : क्या पंजाब के राज्यपाल के रूप में कभी आपको डर नहीं लगा ?

रे : कभी नहीं। डर की कोई वजह नहीं है। वैसे मेरा हमेशा गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पर विश्वास रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे आग की चिंगारियां आग में ही वापस गिरती हैं, जैसे सड़क की धूल सड़क पर गिरती है, जैसे नदी का जल नदी में लौट कर आता है, इसी तरह आप उस परम परमेश्वर से आये हैं और उसी में लीन हो जायेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे यदि कोई सरल और शीघ्र बना दे, तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे कोई डर नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई भी भयभीत है। आप देखें, वे कैसे निष्ठा से काम कर रहे हैं। पंजाबियों का मैं बड़ा प्रशंसक हूं।

—रंजना कक्कड़

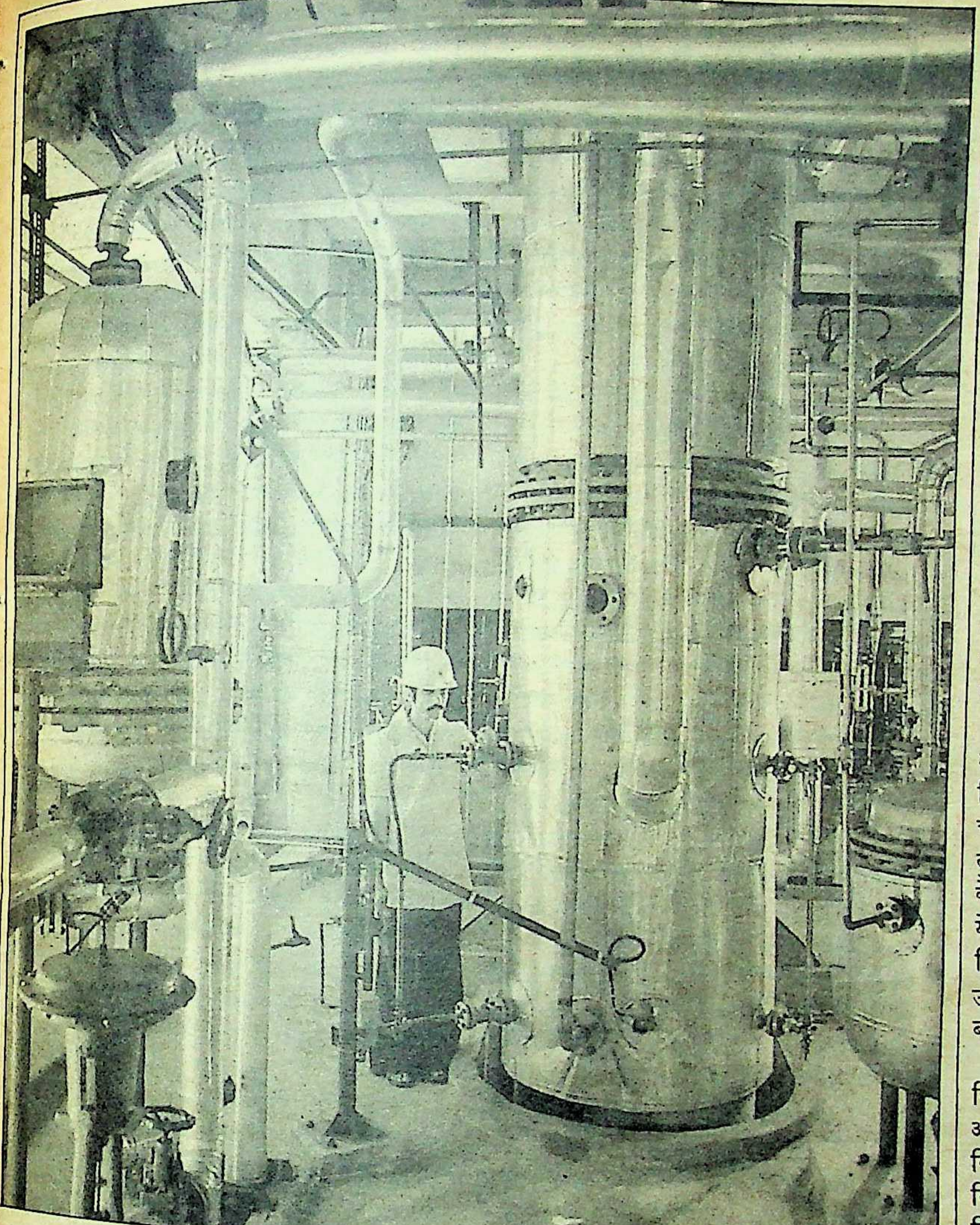

सार्वजनिक क्षेत्र कितना सार्वजनिक है ?

हाल में सार्वजनिक क्षेत्र की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि वह सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र निरंतर मुनाफा कमाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में चलने के क्या कारण हैं ?

जब कोई उद्योगपति कोई ऐसी वस्तु बनाने के लिए पूंजी निवेश करने को तैयार न हो जो कि समाज और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो क्या होता है ? मसलन, सड़कों का निर्माण और सिंचाई के लिए नहरें खोदना आदि। निस्संदेह ऐसी हालत में सिर्फ सरकार को ही यह काम करना पड़ता है। इसी प्रकार तेल की खोज में भारी धन खर्च होता है। हरेक जानता है कि इसमें सफलता हमेशा संदिग्ध होती है। सारी खोदाई व्यर्थ सिद्ध हो सकती है और उसमें लगी तमाम पूंजी बरबाद हो जाती है, लेकिन यह काम भी सरकार को करना होगा, क्योंकि देश के लिए पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। जब सरकार ऐसे काम करती है और सामान उत्पादन या सेवा मुहैया करने के लिए पूंजी लंगाती है और उसे एक मूल्य पर बेचती है, तो इस तरह पूंजी लगाने को सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीनिवेश कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र से इस अर्थ में अलग है। इसका अर्थ है कि सरकार की परिसंपत्तियों का स्वामित्व सार्वजनिक स्वामित्व का एक रूप है।

यह तर्क अनेक मामलों में लागू होता है। क्या आप इस्पात कारखाना चाहते हैं ? भारी मशीनों के निर्माण और जनता के इस्तेमाल की दवाएं बनाना चाहते हैं ? पनबिजली, कोयला, लोहा या अन्य दुर्लभ धातुएं-अल्युमिनियम, बाक्साइट, तांबा आदि के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाना चाहते हैं ? बहुधा ये काम भारत जैसे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में ही किये जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों तक में इसके लिए आवश्यक इतनी बड़ी पूंजी लगाने की हैसियत नहीं होती।

सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत : हाल की एक मिसाल लें। सरकार इस समय निजी क्षेत्र को पहला अवसर देने के पक्ष में है। बंबई के निकट ६६ किलोमीटर की चौड़ी पक्की सड़क बनानी है। इसके लिए काफी धन की दरकार है। काम शुरू करने कें लिए कम-से-कम फी किलोमीटर एक करोड़ रु०। यह तय हुआ कि यह काम निजी उद्योगपतियों को दिया जाये और जो भी यह काम करेगा उसे सड़क का प्रयोग करने वालों से फीस वसूलने की इजाजत होगी। यह फीस सड़क द्वारा प्रदान की गयी सेवा के एवज में होगी। इसमें टाटा तथा रिलायंस उद्योग के अंबानी ने कुछ दिलचस्पी जाहिर की। ऐसी खबर थी कि यह परियोजना व्यावसायिक दक्षता के लिए प्रख्यात धीरूभाई अंबानी को दी जा रही है।

लेकिन मामला यहीं ठप हो गया। गत डेढ़ वर्षों से इस बारे में कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा और किसी को पता नहीं कि अंतत: सड़क कौन बनाने जा रहा है—सरकार या निजी औद्योगिक घराने ? बहरहाल, एक बात साफ है कि ऐसी स्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में प्रवेश करना पड़ता है और कभी-कभी बड़े पैमाने पर।

ठीक यही २०-२५ वर्ष पहले हुआ था। बड़े इस्पात कारखाने बनाने थे। ऐसा कोई इस्पात कारखाना नहीं था जो कच्चे लोहे से बड़ी मात्रा में

क्या सार्वजनिक क्षेत्र निजी बन रहा है ?

समाचार पत्रों में आये दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। "यह बेकार है, राष्ट्रीय साधनों की बर्बादी है," ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। दूसरे दिन फिर प्रधानमंत्री कहते हैं, "यह गड़बड़ है और इसमें सुधार लाजिमी है। यह असहनीय बोझ है और इसे हर सूरत में बंद होना चाहिए। इसे निजी क्षेत्र को सौंप दें और सार्वजनिक क्षेत्र में और पूंजी न लगायें।" फिर किसी दिन प्रधानमंत्री अपनी राय बदल देते हैं और फरमाते हैं, "हम सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसे हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है।"

वह आखिर करना क्या चाहते हैं ? क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र की छुट्टी करना चाहते हैं ? किंतु वह ऐसा नहीं कर सकते। ७५००० करोड़ से अधिक की पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग २१२ संस्थानों में लगी हुई है। इनमें २१ लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और संगठित औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन का एक तिहाई से अधिक इसके हिस्से में आता है। इनमें से हरेक इकाई को अधिक मुनाफे में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आप तब तक कोई मशीन नहीं बेच सकते जब तक उसे कोई खरीदने का इच्छुक न हो। निजी क्षेत्र में कोई भी वह मशीन तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे उस मशीन से मनचाहे लाभ की आशा न हो।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अधिक मुनाफे के नजरिये से अपने उत्पाद की कीमत नहीं वसूल सकती। यही निजी व्यवसायी और सरकार में फर्क है। मान लें शहर में बस परिवहन प्रणाली चलाने की लागत बढ़ जाती है (जैसे डीजल, टायर, बस बाडी और गाड़ी की कीमत बढ़ जाये)। ऐसी सूरत में बस टिकट की दर व्यावसायिक मुनाफे की तुलना में बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं, तो शहर के आम लोगों का कोपभाजन बनना पड़ेगा। या मान लीजिए पन-बिजली उत्पादन की लागत बढ़ जाती है (मसलन कोयला महंगा होने पर) और आपको समुचित लाभ बरकरार रखने के लिए पुनः बिजली की दर बढ़ानी पड़ेगी, किंतु ऐसा करके आप बिजली उपभोक्ताओं को चोट पहुंचायेंगे। इसके अलावा बिजली महंगी करने से फैक्ट्री मालिक को भी अपने सामान की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कभी-कभी कीमतें जितनी बढ़ती हैं, मांग उतनी ही कम हो जाती है और अंततः उत्पाद घट जाता है। फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसरों, और सरकार को उस सामान से प्राप्त राजस्व शुल्क में गिरावट आती है।

दरअसल सरकार उद्योगपतियों के प्रति रियायत की नीति अपनाती रही है। प्रायः फैक्ट्रियों को बिजली घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में कम कीमत में सप्लाई की जाती है, जबकि फैक्ट्रियां बेतहाशा बिजली का इस्तेमाल करती हैं। घरेलू क्षेत्र में एक चौथाई से थोड़ी ही अधिक बिजली खर्च की जाती है और आधी से ज्यादा बिजली का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र करता है। इस आधे भाग की कम-से-कम दो तिहाई निजी क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल की जाती है। दूसरे शब्दों में देश में कुल उत्पादित बिजली (जो पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन है) का कम-से-कम एक तिहाई निजी व्यवसायियों को बहुत कम कीमत पर और दरअसल घाटे में बेची जाती है।

अन्य मिसालें भी हैं। इस्पात प्लांट प्रायः कुछ किस्म के इस्पात को निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता को सामान्य उपभोक्ता की तुलना में कहीं सस्ती दर पर बेचते हैं। इससे लाभान्वित होने वालों में रेफ्रिजरेटरों के निर्माता शामिल हैं, किंतु रेफ्रिजरेटर वे सस्ती दर पर नहीं बेचते। वे अपना काफी ऊंचा मुनाफा बनाये रखते हैं। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र को अधिक मुनाफा कमाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में उसे अपने लाभ की बलि चढ़ानी पड़ती है।

ऐसी स्थिति में आप सार्वजनिक क्षेत्र के मत्थे अधिक मुनाफा न कमाने का दोष कैसे मढ़ सकते हैं ? यह सरकार की अपनी नीति है जो उसके कामकाज को तय करती है। इसके अलावा इन इकाइयों को चलाने वालों की अपनी अक्षमता का भी मुद्दा है। यदि दोनों में सुधार किया जाये, तो इसका हर कोई स्वागत करेगा। यदि विचार निजी व्यवसायियों के मुनाफे में वृद्धि का है, तो फिर बात दूसरी है।

कथा का एक अन्य पहलू भी है। यह जगजाहिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों को सत्तारूढ़ लोगों को मोटी रकम रिश्वत में देनी पड़ती है। इसे साबित नहीं किया जा सकता पर यह है सच। विदेश से विमान खरीद कर लाया जाता है और सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत देने के लिए उसकी कहीं ऊंची कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी तरह निजी क्षेत्र की फर्मों से खरीद में रिश्वत चलती है। ऊंचे स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार से उत्पादन दर बढ़ती है और मूल्यवृद्धि होती है, किंतु इकाई के हिसाब-किताब में यह (रिश्वत) दिखायी नहीं जाती। दिखाया जाता है, तो थोडा मुनाफा या घाटा।

क्या इस दुधारू गाय को दुहने के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देंगे ? नहीं। वह चाहेंगे कि यह मुनाफा बढ़ जाये और स्थिति में भरसक सुधार हो जाये। इसके रास्ते हैं। पहला कदम उठाया जा चुका है। जब कभी लागत बढ़ती है कीमतें बढ़ जाती हैं। हाल की इस्पात, कोयला की मूल्यवृद्धि इसकी मिसाल है।

दूसरा कदम है इकाइयों को नयी किस्म की कंपनी में बदल दो जिससे इकाई के प्रबंधकों को संसद में जवाबदेही के कानूनी बंधन से मुक्ति मिले। इसके अलावा निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोगों को इकाई चलाने और निर्णय करने का अधिकार दो। इसके बाद भी आप भ्रष्ट तरीकों से काफी रकम बना सकते हैं और खर्च के कुछ अहम जिंसों में कटौती कर सकते हैं, जिसे करने की आजादी निजी व्यवसायी को है। उदाहरण के लिए अगर आप बड़ी तादाद में कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं, तो आराम से यह कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कार्यक्षमता का बहाना है। इसका मतलब है मुनाफा। यही निजी व्यवसायी करता है। यही संयोगवश सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने भी करने का फैसला किया है। यह सब एक ऐसी समिति के सुझाव के आधार पर किया गया है जिसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री के एक समय के सलाहकार अर्जुन सेनगुप्त।

इस्पात का उत्पादन कर सकता। देश को विभिन्न प्रकार के इस्पात सामानों की आवश्यकता थी जिससे नयी फैक्ट्रियों के लिए बड़ी और छोटी मशीनें बनाई जा सकें। मकानों, सड़कों, पुलों और अन्य सैकड़ों कामों के लिए इस्पात की जरूरत थी। इसका बड़ी मात्रा में आयात करना असंभव था, क्योंकि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी।

इसी प्रकार बड़ी और भारी मशीनों का उत्पादन करना और ऐसी मशीनों के कलपुरजे बनाना जरूरी था। बिजली उत्पादन के लिए टर्बाइन्स अत्यधिक महत्वपूर्ण जिंस थी, किंतु उद्योगपति यह काम नहीं कर सकते थे और न वह इसके लिए राजी होते। इसके लिए भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की क्षमता से अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। फिर पूंजी लगाने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। इसका मतलब है कि उद्योगपति को काफी समय तक अपनी लागत की कोई वसूली न होती। वह कभी इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा न करता। सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोई निश्चित गारंटी नहीं थी, जैसा कि आज भी नहीं है कि जो भी उत्पादन होगा वह बिकेगा भी। इसका अर्थ है कि समुचित लाभ हो ही यह जरूरी नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका उद्योगपति उत्पादन कर सकता है सामान्यतः वांछित लाभ पा सकता है।

इस प्रकार केवल सरकार ही इस स्थिति में थी जो करदाताओं से धन एकत्र कर सकी, देश के भीतर और बाहर से ऋण ले सकी और यह सारी पूंजी इन उद्योगों की स्थापना में लगा सकी। उसे अच्छी तरह पता था कि हरेक पूंजी निवेश से वह माकूल मुनाफा नहीं हो सकता जिसकी आशा कोई व्यवसायी अपनी पूंजी लगाकर करता है। किंतु उसे यह भी अहसास था कि दूसरा विकल्प है पूरी तरह आयात पर निर्भर करना। ऐसी स्थिति में प्रायः विदेशी सरकारों के रहमोकरम पर रहना पड़ता है, मसलन अमरीकियों ने इस्पात प्लांट की आपूर्ति

करने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन ने एक प्लांट दिया और जर्मनी ने दूसरा। तीसरा हमें सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। इस प्रकार तीन बड़े इस्पात प्लांट जो देश के विभिन्न भागों—दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), राउरकेला (उड़ीसा) और भिलाई (म०प्र०) में लगे। आज इनकी देखरेख भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) करता है और देश के कुल इस्पात के अधिकांश भाग का उत्पादन ये तीनों प्लांट करते हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) देश का एक अन्य विशालकाय सार्वजनिक क्षेत्र है। अमरीकी व्यावसायिक पत्रिका 'फार्चून' ने इसे विश्व की सर्वाधिक पूंजी और बिक्री वाली प्रथम श्रेणी की कंपनियों में शामिल किया है। यह संगठन कुछ दूसरी इकाइयों सहित, विदेशों से आयातित कच्चे पेट्रोलियम का परिशोधन करता है और देश में उसका उत्पादन करता है। इसी के अंतर्गत खाना पकाने की गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन तेलों का देश में उत्पादन होता है। इसके बिना देश को कच्चे पेट्रोलियम की जगह ये सब जरूरी जिंसे आयात करनी पड़तीं। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का खर्च कहीं ज्यादा बैठता'।

देश में तेल स्रोतों की खोज के लिए जगह-जगह खोदाई करनी पड़ती है और यह बहुत महंगा काम होता है। इसके अलावा खोदाई गहरी-से-गहरी हो सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि खोदाई से मिले तेल से खर्च हुई रकम वसूल हो पायेगी या नहीं। दूसरे शब्दों में इस निवेश में अनिश्चितता बहुत अधिक होती है। कभी-कभी खर्च की गयी सारी रकम डूब भी जाती है, किंतु इसके बिना तेल की खोज का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

कोई भी उद्योगपति यह 'जरूरी' फिजूलखर्ची करने को तैयार नहीं होगा और जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इसे करती है, तो उसके लिए पूंजीनिवेश से फौरी लाभ कमाना आसान नहीं। इसलिए यह ऐसा क्षेत्र है जहां यह जानते हुए भी कि यह व्यापारिक लाभ की शक्ल में मुनाफे का अथवा घाटे का सौदा हो सकता है, पूंजी लगानी पड़ती है, क्योंकि वह अर्थतंत्र के लिए, निजी व्यवसायियों के लिए और साथ ही पेट्रोल, यात्री कार, सार्वजनिक बस और डीजल चालित रेल गाड़ियों से यात्रा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। आवश्यक दवाएं, छोटी-बड़ी मशीनें, रेल और विमान यात्रा, नगर परिवहन सेवा, नहर व बड़े पंपों द्वारा सिंचाई, बिजली तथा अनगिनत सामानों का उत्पादन आज सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत इलेक्ट्रानिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, इंडियन आयल, कोल इंडिया, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो महत्वपूर्ण सामानों का उत्पादन करते हैं अथवा सेवाएं उपलब्ध करते हैं। इनमें भारी पूंजी लगी है। इसके अलावा दूध और दुग्ध उत्पादों, पावरोटी और मक्खन, बेकरी उत्पाद, पर्यटन और होटल सेवा, विमान-रेल यात्रा, टेलीफोन संयंत्रों, छपाई और प्रकाशन सेवा और यात्री कारें—जैसे मारुति-का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व

	१९८०/८१	१९८३/८४	१९८४/८५	१९८५/८६
जारी इकाइयों की संख्या	१६८	२०१	२०७	२११
पूंजीनिवेश	१८२०७	२९८५१	३६३८२	४३०९६
कुल व्यापार	२८६३५	४७२७२	५४७८४	६२२२१
सकल लाभ	१४१८	३५६५	४६२८	५३१९
टैक्स	२२२	१२३९	११९०	१००१
कर चुकाने के बाद शुल्क आय	(—)२०३	२४०	९०९	११९९
पूंजीनिवेश के अनुपात में सकल आय	७.८	११.९	१२.७	१२.३

(समस्त आंकड़े करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के फायदे : सार्वजनिक क्षेत्र में भारी पूंजीनिवेश के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों की तुलना में भारत औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश बना है। औद्योगिक उत्पादन की मात्रा के अनुसार भारत का विश्व में १० वां स्थान है। देश अपने क्षेत्र और आबादी के लिहाज से बहुत विशाल है, इसलिए दसवीं श्रेणी का अर्थ यह नहीं कि बहुसंख्य देशवासियों की खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी पर्याप्त औद्योगीकरण हो गया है। फिर भी भारत उन गिने-चुने देशों में एक है जहां जनता द्वारा उपयोग की जा रही अधिकांश वस्तुएं देश में ही पैदा की जाती हैं।

क्या इस क्षेत्र को समाप्त किया जा सकता है? क्या किसी ने गंभीरतापूर्वक सोचा है कि किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ आंकड़े मददगार साबित होंगे। राष्ट्र को १९८४-८५ की अपनी कुल आय का १८ प्रतिशत उत्खनन और निर्माण (खान—फैक्ट्रियां और छोटी इकाइयां जो औद्योगिक सामान बनाती हैं) से हुआ। कुल आय ५७०१४ करोड़ रु० थी और खानों और फैक्ट्रियों का अंश था १०२६२ करोड़ रुपए। खानों से हुई आय का तीन चौथाई भाग सार्वजनिक क्षेत्र का था। और एक तिहाई से अधिक आय सार्वजनिक क्षेत्र के प्लांटों से हुई (देखें तालिका)।

सार्वजनिक क्षेत्र से हुए रोजगार के साधनों को लें। १९६१ में सरकारी फैक्ट्रियों में औसतन रोजाना ५८४००० लोगों को और निजी फैक्ट्रियों में ३३ लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया था। १९८० में सरकारी फैक्ट्रियों में रोजगार बढ़कर १७ लाख से अधिक हो गया जबकि निजी क्षेत्र में यह बढ़कर ५३ लाख पहुंच गया। पहले में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई जबकि दूसरी २० वर्षों में अपना योगदान दुगना भी नहीं कर सकी।

सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की पूंजी १९७०-७१ में ३६०६ करोड़ रु० थी जो १९८५-८६ में बढ़कर ४३००० करोड़ हो गयी। ऐसी इकाइयों की संख्या १९७०-७१ में ८७ थी जो १९८५-८६ में बढ़कर २०७ हो गयी।

यह जिन सामानों का उत्पादन करता है अब उसकी महत्ता को लें। कोयला, अबरख, अल्युमिनियम, बाक्साइट, लिगनाइट तथा अन्य महत्वपूर्ण धातुएं पूर्णतया सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन में टाटा की बहुत थोड़ी साझेदारी है। पेट्रोलियम का परिशोधन पूर्णतया सावजनिक क्षेत्र में होता है। ९९ प्रतिशत से अधिक बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। देश की भारी मशीनों के दो तिहाई से अधिक भाग का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। बड़े शहरों में कुल खपत होने वाले दूध की सप्लाई सार्वजनिक क्षेत्र करता है। तमाम अनाज जो राशन की दुकानों से सप्लाई होता है, उसे किसानों से खरीद कर बेचने वाला संस्थान भारतीय खाद्य निगम है जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक संगठन है। धातुओं और खनिजों का आयात-निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। रेल और विमान सेवा पूर्णतया इस क्षेत्र के हाथ में है। इसी तरह टेलीफोन संयंत्रों का उत्पादन है। १०० से अधिक सूती मिलें नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के स्वामित्व में हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है।

इन तमाम इकाइयों का समूचा उत्पादन जारी रखना, दरअसल उत्पादन को बढ़ाना है। हरेक इकाई भरपूर मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं हो सकती और न ही हरेक इकाई निजी क्षेत्र को सौंपी जा सकती है। क्या किया जाये अथवा क्या किया जायेगा, यह बिलकुल अलग मामला है (देखें बाक्स)।

—कुमारेश चक्रवर्ती

केंद्रीय मंत्रिमंडल : नये रिकार्ड

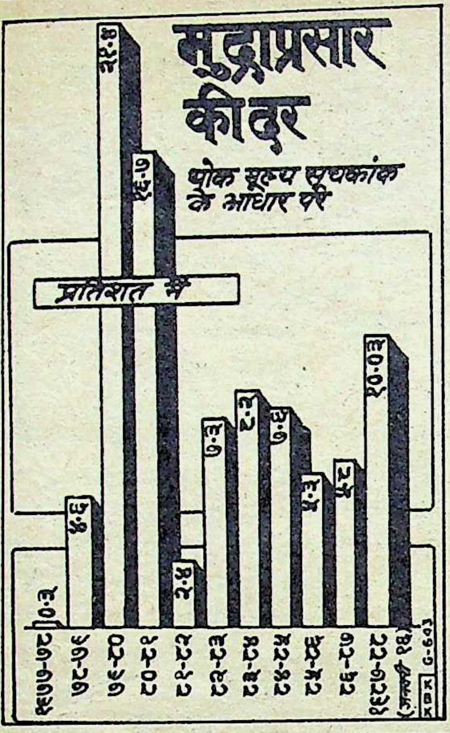

राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में जनार्दन पुजारी ही एकमात्र मंत्री ऐसे रहे, जिन्होंने छह वर्षों तक लगातार एक ही विभाग-वित्त मंत्रालय में टिके रहने का अभूतपूर्व रिकार्ड बनाया है। वह राजीव गांधी के पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में भी इसी विभाग में थे। जनार्दन पुजारी को इस ताजे फेरबदल में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री बनाया गया है।

हंसराज भारद्वाज ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो पिछले ३७ महीनों से विधि और न्याय मंत्रालय में हैं और इस बार भी उनका विभाग नहीं बदला।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ९२ लोग मंत्री बने जिनमें से आज ३२ लोग मंत्रिमंडल के बाहर हैं।

मंत्रियों के विभागों का फेरबदल इतनी तेजी से हुआ कि औसतन एक मंत्री एक विभाग में छह से आठ महीनों से अधिक एक पद पर नहीं रहा।

राजीव गांधी ने ३७ महीनों में अपने मंत्रिमंडल में छोटे-बड़े परिवर्तनों को मिलाकर कुल २३ बार फेरबदल किया अर्थात राजीव गांधी ने औसतन हर ४८ दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया।

अन्न और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने तीन साल में पांच मंत्री देखे। राजीव सरकार के गठन के समय ३१ दिसंबर, १९८४ को राव वीरेंद्र सिंह इसके प्रमुख बने। नौ मास बाद उनके स्थान पर के०पी० सिंह देव आये, लेकिन चार मास में ही उनके त्यागपत्र देने पर पी० शिवशंकर इस मंत्रालय के मंत्री बने। साढ़े तीन मास में ही उनकी जगह पर हरकिशन लाल भगत बिठा दिये गये। वह २१ महीने इस पद पर रहे। अब यह विभाग राज्यमंत्री सुखराम को सौंप दिया गया हैं।

इसी प्रकार नागरिक उड्डयन विभाग में तीन सालों में राजीव गांधी, बंसीलाल, मोहसिना किदवई, जगदीश टाइटलर आये और गये। अब यह मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्य देख रहे मोतीलाल वोरा को अस्थायी तौर पर सौंप दिया गया है। बंसीलाल इस विभाग में सिर्फ २० दिन रहे।

पर्यटन विभाग में भी तीन सालों में पांच मंत्री गये-आये। शुरू में राजीव गांधी ने इसका काम देखा, फिर हरकिशन लाल भगत आये। साढ़े सात महीने में ही उन्हें अन्यत्र भेजकर मुफ्ती मोहम्मद सईद को यह विभाग सौंपा गया। जुलाई '८७ में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अस्थायी तौर पर सात महीनों तक जगदीश टाइटलर ने इसका काम देखा। अब मोहसिना किदवई को यह विभाग अस्थायी तौर पर दिया गया है।

पर्यटन विभाग में पांच मंत्रियों के अलावा तीन वर्षों में तीन राज्यमंत्री भी रहे—संतोष मोहन देव (पांच महीने), अशोक गहलोत (आठ महीने) और गुलाम नबी आज़ाद (आठ महीने)।

इसी तरह स्टील और खान मंत्रालय को वसंत साठे, कृष्णचंद पंत, फिर वसंत साठे ने क्रमश: ९, १८, ३ महीने संभाला। अब सात मास से माखनलाल फोतेदार इस विभाग का काम देख रहे हैं।

संचार मंत्रालय को राम निवास मिर्धा, बी०एन० गाडगिल और अर्जुन सिंह ने संभाला, अब वसंत साठे इसे देख रहे हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मोहसिना किदवई और पी०वी० नरसिंहराव के बाद मोतीलाल वोरा को सौंपा गया है।

विदेश मंत्रालय तो पांच हाथों से घूमकर फिर राजीव गांधी के पास आ गया। पहले नौ महीने तक राजीव गांधी ने इस विभाग का काम देखा, फिर बलिराम भगत सात मास तक रहे, उनके बाद आये पी० शिवशंकर, सिर्फ छह मास तक टिक सके, फिर अक्तूबर १९८६ में यह विभाग नारायण दत्त तिवारी को सौंपा गया, लेकिन राजीव गांधी ने २५ जुलाई, १९८७ को यह विभाग उनसे छीनकर फिर अपने पास रख लिया। इस प्रकार १९८६ में ही इस विभाग ने तीन मंत्री देखे। गनीमत है, इस नये मंत्रिमंडल के फेरबदल में इस विभाग को राजीव गांधी ने नहीं छेड़ा।

राजीव गांधी के पास विज्ञान, टेक्नालाजी, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग स्थायी तौर पर रहे हैं, लेकिन अनेक अन्य विभागों पर भी उन्होंने छलांगें लगायी हैं। ३१ दिसंबर, १९८४ को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद १५ दिनों तक उन्होंने वाणिज्य और आपूर्ति, उद्योग व कंपनी मामले तथा प्रशासनिक सुधार विभागों का काम देखा। विदेश विभाग उनके पास ९ महीनों तक रहा और आज भी उनके पास है। १९८५ के अंत में दो मास के लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय का काम देखा। जून १९८६ में जल संसाधन विभाग उन्होंने अपने अधीन कर लिया, उसके बाद एक वर्ष, पांच मास तक उन्होंने सुरक्षा मंत्रालय और साथ ही ढाई वर्षों तक योजना मंत्रालय को संभाला।

नारायण दत्त तिवारी सितंबर १९८५ में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और २८ महीनों में उन्होंने उद्योग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विदेश, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय का कार्य संभाला तथा अब भी उनके पास वित्त और वाणिज्य मंत्रालय हैं।

राष्ट्रीय आय

१९८६-८७ के राष्ट्रीय विकास और ह्रास के आंकड़े सरकार ने प्रकाशित कर दिये हैं, जिसके अनुसार कुल राष्ट्रीय आय में ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९८५-८६ में राष्ट्रीय आय १३८६११ करोड़ थी, जो १९८६-८७ में बढ़कर १४३९३५ करोड़ हो गयी।

१९८६-८७ में कुल घरेलू उत्पाद में ११.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू कीमतों के आधार पर १९८६-८७ में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय २९७५ रुपए आंकी गयी, जबकि १९८५-८६ में यह २७२१ रुपए थी।

इस दौरान घरेलू बचत की राशि ६३४१३ करोड़ थी।

खाद्यान्न उत्पादन में १९८६-८७ में ४.२ प्रतिशत की कमी आयी है। १९८५-८६ में कुल खाद्यान्न उत्पादन १५.०४ करोड़ टन हुआ था जो१९८६-८७ में घटकर १४.४१ करोड़ टन रह गया।

खनिज उत्पादन में कुल ११.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में यह वृद्धि १३ प्रतिशत, कोयले में ९.३ प्रतिशत तथा खनिज लोहे में १०.८ प्रतिशत रही। बिजली गैस और जल-आपूर्ति में ११.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

—संयोजन: विनोद मिश

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्ष्या के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठाले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'किउब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के इन्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्ष्या मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सावधान-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

[redacted]

क्या करे रेखा?

कभी ज्योतिषियों के नाम मात्र से लाल-पीली हो जाने वाली रेखा आजकल हर ज्योतिषी की आवभगत करती नजर आ रही है। उसके इस कायाकल्प के कई कारण हैं—(१) उसके महबूब अब उसकी साया मात्र से कतरा जाते हैं—पिछले दिनों वह उनसे मिलने के लिए दिल्ली, ऊटी और मद्रास गयी, लेकिन वह पगहा तुड़ा कर भाग निकले। (२) अब कोई भी फिल्म-निर्माता उसे साइन करने के लिए नहीं आता, जबकि उसने अपनी 'प्राइस' आधी से भी कम कर दी है। (३) उसके प्रशंसकों के पत्र घटकर चौथाई भी नहीं रह गये हैं। (४) पिछले दो वर्षों से उसके स्टाफ उससे लड़-झगड़ कर नौकरी छोड़कर चले जाते रहे हैं और अब वह बड़े प्यार से उनके साथ बरताव करने के लिए तैयार है, तो कोई भी उसके पास काम करने के लिए राजी नहीं है। (५) आयकर अधिकारियों ने उसे बेतरह परेशान करना शुरू कर दिया है। (६) उसकी फिल्मों के खरीदने के लिए न तो वितरक आगे आते हैं और न ही फायनेंसर, आदि-आदि।

१९८७ में रेखा की एक दर्जन से अधिक तैयार फिल्मों में सिर्फ 'प्यार की जीत' और 'जान हथेली पे' ही प्रदर्शित हो सकी। मनोज कुमार तथा गुलजार जैसे बिकाऊ निर्देशकों की फिल्मों ('क्लर्क' तथा 'इजाजत') को छूने के लिए कोई फिल्म-वितरक तैयार नहीं है और अगर किसी ने इसके वितरण अधिकार खरीद भी लिये, तो प्रिंट लेने में हीला-हवाली कर रहा है। गुलजार ने बड़े मन से 'इजाजत' बनायी। जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा, उसने न केवल फिल्म की, बल्कि रेखा के सशक्त अभिनय की तारीफ भी की और उसकी तुलना गुलजार की 'आंधी' में सुचित्रा सेन, 'मौसम' में शर्मिला टैगोर तथा 'कोशिश' में जया भादुड़ी से की।

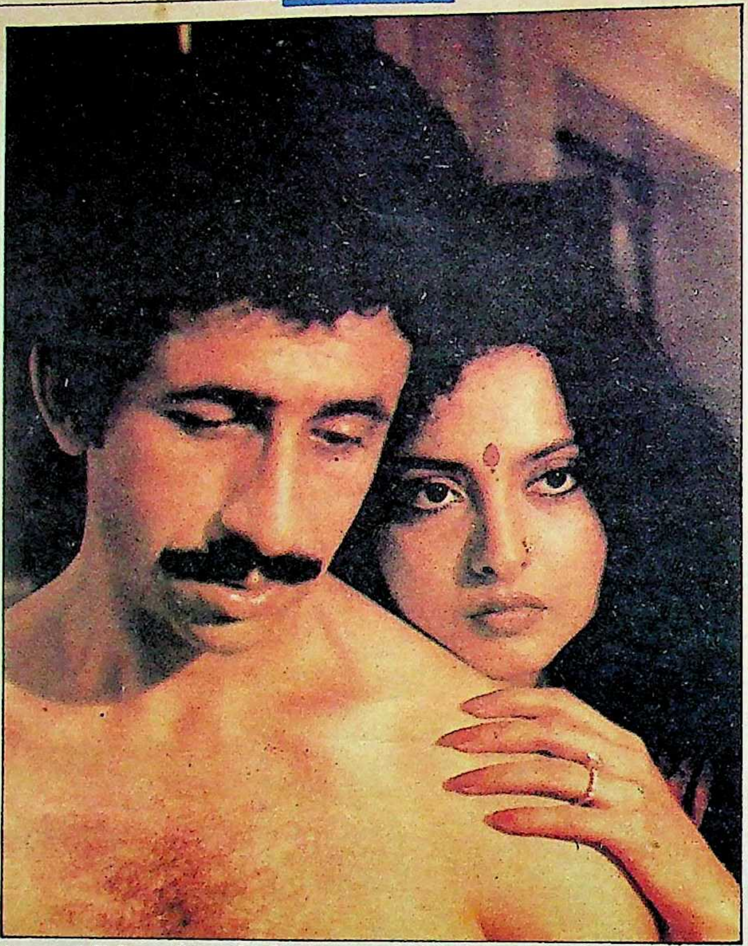

'इजाजत' में रेखा और नसीरुद्दीन शाह

छाया : दुर्गा प्रसाद

लेकिन इसके बावजूद, दो वर्षों से तैयार 'इजाजत' प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। रेखा को श्रीमती तेजी बच्चन से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह कर 'शहंशाह' के प्रदर्शन की जो तारीख मुकर्रर की, उसके ठीक एक पखवारे पहले 'शहंशाह' के सारे कष्ट दूर हो गये। फिर फिल्मी शहंशाह से रेखा के भी तो 'कुछ' रिश्ते हैं।

[redacted]

हेमा की नयी भूमिका

प्रकृति से कवयित्री, स्वभाव से समाज सेविका तथा आदत से कठोर अनुशासनबद्ध जया चक्रवर्ती की नर्तकी बेटी- हेमामालिनी बड़ी होकर पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन नर्तकी से बन गयी अभिनेत्री। फिर एक अभिनेता की दूसरी पत्नी। बचपन से पत्रकार बनने की ललक के ही कारण उसने थोड़ी-सी हिचक के बाद एक प्रकाशक को अपनी पत्रिका की बतौर संपादिका नाम उपयोग करने की अनुमति दे दी, लेकिन पत्रकारिता का क, ख, ग तक न जाननेवाली हेमामालिनी अपर्णा सेन नहीं बन सकी, सिर्फ अपना नाम देकर सुर्खियां हासिल कर लेने वाली मात्र हेमा भर ही रह गयी।

अपने अफेयरों के बारे में अंट-शंट लिखनेवाले गाशिप-लेखकों एवं गाशिप पत्रिकाओं को भी वह 'सच्ची' पत्रकारिता का ककहरा सिखाना चाहती थी, लेकिन आफत की मारी किसी फिल्मी पत्रिका ने उसे घास तक नहीं डाली। खोजी पत्रकारों से सौ कदम दूर रहनेवाली हेमा की इस इच्छा को पूरा किया, विज्ञापन एवं कलात्मक लघु फिल्में बनानेवाले निर्माता शकील खान तथा निर्देशक राजन जौहरी ने उसे अपनी नयी फिल्म 'षड्यंत्र' में खोजी पत्रकार की भूमिका देकर, जिसमें वह अपने पति (राज बब्बर) के हत्यारे का पता लगाकर एक बहुत बड़े 'षड्यंत्र'

'षड्यंत्र' में हेमामालिनी

छाया : [illegible]

का परदाफाश करती है। यह बात दूसरी है कि यह भूमिका पहले रामेश्वरी निभा रही थी, लेकिन 'दुल्हन वही जो पिया मन भाये' से अपने को जया भादुड़ी तथा प्रेम कपूर के सीरियल से 'प्रथम प्रतिश्रुति' तक अपने को जया भादुड़ी मान बैठनेवाली रामेश्वरी ने निर्माता को कुछ ऐसा नाच नचाया कि उसने उसे फिल्म से निकाल कर वह भूमिका हेमामालिनी को थमा दी। सवाल पुराने शौक का था या बेकारी का कि हेमा ने तुरंत 'षड्यंत्र' की भूमिका स्वीकार कर ली।

छाया : रणजित घटक

'कौन रोकेगा मुझे' के मुहूर्त पर सुनील दत्त, अमृता सिंह और विनोद खन्ना

सोमदत्त की बेवफाई

समय के साथ रिश्ते कितने बेमानी हो जाते हैं, इसकी ताजी मिसाल हैं सुनील दत्त के छोटे भाई सोम दत्त जो अपने इस अभिनय शून्य एकलौते भाई को, मां के निर्देश पर, हीरो बनाने के लिए अपार धनराशि खर्च कर १९६८ में (फिल्म) 'मन का मीत' बनायी, लेकिन न फिल्म चली न हीरो सोमदत्त। किंतु फिल्म की हीरोइन (लीना दावरकर) तथा खलनायक (विनोद खन्ना) अपनी इस पहली ही फिल्म से फिल्मी दुनिया में छा' गये।

'मन का मीत' की व्यावसायिक असफलता ने सुनील दत्त की कमर तोड़ दी, लेकिन इसकी शिकन न तो उन्होंने चेहरे पर आने दी और न ही बीवी नर्गिस ने। फिल्म अभिनय के मैदान में पहले ही झटके में उखड़ गये सोमदत्त के पांव दूसरे व्यवसाय में जमा कर सुनील दत्त ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन छोटे भाई ने २ फरवरी, १९८८ को जब बड़ी शानोशौकत से अपनी सिनेमा स्कोप फिल्म 'कौन रोकेगा मुझे' का मुहूर्त किया, तो फिल्म के निर्देशन का भार बड़े भाई को न देकर 'जलवा' के चर्चित निर्देशक पंकज पाराशर को दे दिया और-तो-और अपने भतीजे संजय दत्त को, जो पुनः स्टार बनने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं, भी कोई भूमिका नहीं दी और 'मन का मीत' के खलनायक विनोद खन्ना को हीरो बना दिया। सुनील दत्त ने बतौर मेहमान मुहूर्त में आकर अपनी रस्म अदायगी तो कर दी, लेकिन उनके मुस्कराते चेहरे के भीतर छोटे भाई के व्यवहार का जो रंज छिपा था, वह बतर्ज 'खत का मजमूं भांप लेते हैं लिखावट देखकर' साफ जाहिर हो रहा था। उन्हें एक रंज यह भी था कि सोम दत्त, सुनील दत्त के साले अनवर हुसेन की मौत के कारण, लोगों के समझाने पर भी मुहूर्त की तिथि टालने के लिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन संजय दत्त ने 'मैं हारूंगा नहीं' स्टाइल में न केवल मुहूर्त एवं पार्टी का बहिष्कार किया, बल्कि अपने चाचा के रवैये के विरुद्ध जंग का भी ऐलान कर दिया।

जैकीश्राफ, किमी कातकर और सन्नी देवल

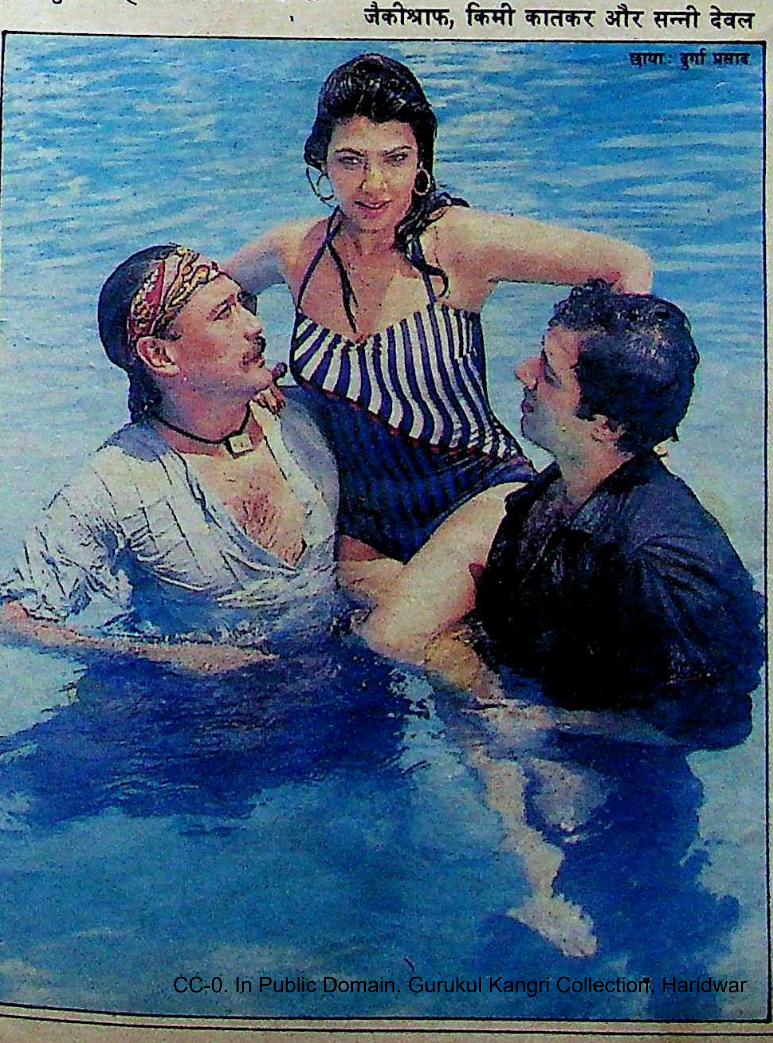
छाया : दुर्गा प्रसाद

किमी कातकर की सांसत

किमी कातकर को लेकर जिस तरह उसके दो प्रेमियों ने शूटिंग के समय आपस में गुत्थम-गुत्था और हैरतअंगेज गालियों के अति हैरतअंगेज सीन दिये, उससे उसके निर्माता-निर्देशक तो परेशान हैं ही (कि वे सीन फिल्म की पटकथा में नहीं थे), खुद किमी कातकर भी परेशानी में फंस गयी है। न तो वह और न ही उसकी मां कोई ऐसा रामबाण नुस्खा निकाल पा रही हैं कि कैसे वे इन प्रेमी नायकों को सेट पर भी और सेट के बाहर 'टैकल' कर सकें। सेट के बाहर तो वे इसे बखूबी निबटा सकती हैं, लेकिन सेट पर उस समय मुसीबत हो जाती है जब एक अदद से ज्यादा प्रेमी-नायक एक ही सीन में एक-दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं।

ऐसे ही एक वाकये में वह हादसे का शिकार हो गयी। उसके दो अलग-अलग प्रेमी सन्नी देवल तथा जैकी श्राफ के साथ उसे एक स्विमिंग पूल पर सीन देना था। मामले को संतुलित बनाये रखने के लिए खाली समय उसने सन्नी या जैकी के साथ बिताने के बजाय सहायक डायरेक्टरों के साथ सीन समझने के बहाने बिताना ज्यादा ठीक समझा। उसकी इस हरकत से झल्लाये दोनों दीवाने नायक उस समय आपस में उलझ गये, जब उनमें से जैकी ने जाट-जूनियर पर कुछ फब्तियां कस दीं, बस दोनों डूबती हीरोइन को संभालने का सीन देते-देते कुछ ऐसे आपस में गुत्थम-गुत्था हुए कि किमी को लगा तरणताल में उसका तारण अब हुआ-तब हुआ। लेकिन तैराकी सीखना उसके काम आया और किसी तरह चक्रव्यूह में फंसे दोनों अभिमन्युओं को आपसी फैसला खुद वहीं कर लेने के लिए छोड़ कर वह ताल से बाहर निकल आयी।

—अखबारी लाल

दिलीप वेंगसरकर

व्यक्ति को सजा या प्रतिभा को?

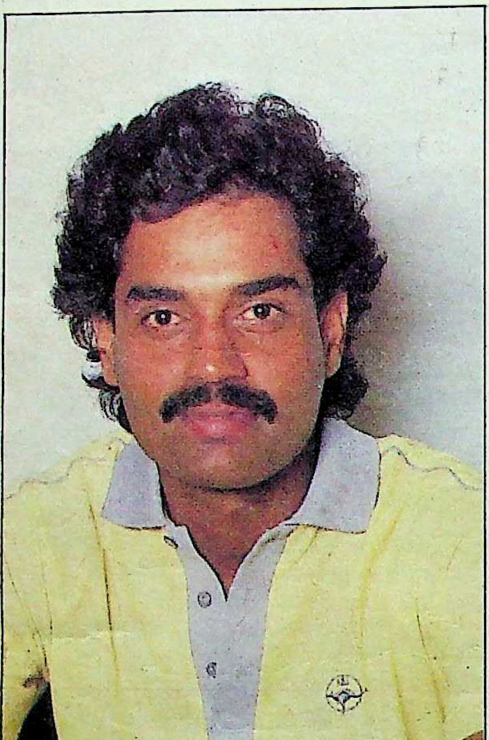

आम तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों और कप्तान के चयन को लेकर विवाद का विषय बनता है और श्रृंखला समाप्ति पर उसकी फिर थोड़ी-बहुत आलोचना हो जाती है। लेकिन इस बार उसके तानाशाही रवैये और एक गैरजरूरी फैसले को लेकर उसकी जमकर आलोचना और निंदा हो रही है। हाल में खतम हुई भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला में तीन टेस्टों और दो एक दिवसीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले दिलीप बलवंत वेंगसरकर पर बोर्ड ने छह माह के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी और दस हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया है। उन पर विल्स ट्राफी, रणजी ट्राफी, एशिया कप (अब स्थगित कर दिया गया है) और शरजाह कप खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास या खेल इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी को इतनी कड़ी सजा दी गयी है।

विवाद की वजह: विश्व के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक दिलीप वेंगसरकर का जुर्म यह है कि उन्होंने बोर्ड के साथ हुए अनुबंध की एक शर्त का बार-बार चेतावनी देने पर भी पालन नहीं किया। शर्त यह थी कि टीम का कोई भी सदस्य या कप्तान जारी श्रृंखला के बारे में किसी पत्र-पत्रिका में लेख या टिप्पणी आदि नहीं लिखेगा। वेंगसरकर ने इस शर्त को अनदेखा किया और लगातार एक सिंडीकेट के माध्यम से अखबारों में अपनी राय जाहिर करते रहे। बोर्ड ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की, लेकिन वेंगसरकर ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच पूरी क्रिकेट टीम वेंगसरकर के समर्थन में खड़ी हो गयी। सीधे शब्दों में खिलाड़ियों ने बोर्ड के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी और यह धमकी भी दे दी कि यदि उसने वेंगसरकर के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो वे मैच का बहिष्कार करेंगे। बोर्ड ने घबड़ाकर कारण बताओ नोटिस की अवधि बढ़ा दी। वह बीच श्रृंखला में एक नया विवाद खड़ा करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था।

१४ दिसंबर को बोर्ड ने एक और नोटिस इस संबंध में वेंगसरकर को भेजी। वेंगसरकर ने जवाब देने के लिए १० दिन की मुहलत मांगी जो २२ दिसंबर को हुई बोर्ड की बैठक में उन्हें प्रदान कर दी गयी। वेंगसरकर ने इसका जवाब दिया, परंतु उससे बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ और उसने वेंगसरकर को सजा सुना दी।

निस्संदेह वेंगसरकर ने करार का उल्लंघ किया है, लेकिन इस बात पर गौर करना बहु जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? वेंगसरक और उनके समर्थक खिलाड़ियों की दलील थी कि ह दिन होने वाले खेल पर लिखने का प्रतिबं एकतरफा था। विरोधी टीम के कप्तान यानी विवियन रिचर्ड्स धड़ल्ले से अखबारों में लिख र थे। रिचर्ड्स के लेखन का उन पर मनोवैज्ञानि प्रभाव पड़ रहा था, ऐसा भारतीय खिलाड़ियों क मत था। उनका कहना था कि रिचर्ड्स की तरह य जरूरी था कि भारतीय टीम का कप्तान भी अप और अपने खिलाड़ियों के विचार लेखन के जरि लोगों के सामने रखे। दलील झूठी नहीं लगती। य बात इसी से साफ हो जाती है कि यदि यह बया केवल वेंगसरकर का होता, तो पूरी-की-पूरी टी मैच खेलने की धमकी न देती, जबकि वेंगसरकर कप्तान बनने के बाद वैसे ही टीम में कई गुट बने हु थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी वाकई ऐसा महसूस करते थे।

इस प्रकरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पह है—वेंगसरकर के खिलाफ कार्रवाई करने क तरीका। बोर्ड ने इस पूरे मामले में जिस तरह क चालाकी और कायरता दिखायी, वह निश्चय ह शर्मनाक है। इस भय से कि कहीं सचमुच ही पू टीम खेलने से इनकार न कर दे, वह मामले क टालता रहा। यदि उस समय वह यह कार्रवा करता, तो पूरा दौरा खतरे में पड़ जाता और उ काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। फि श्रृंखला समाप्त होने के बाद उसने वेंगसरकर क सजा सुना दी, क्योंकि अब उसे किसी बात का खत नजर नहीं आ रहा था। सवाल उठता है कि य उसकी दृष्टि में वेंगसरकर का अपराध इतना ह बड़ा था, तो क्यों नहीं उसने उसी समय कार्रवा की, जब उसकी नोटिस के बावजूद वेंगसरकर अपना लेखन जारी रखा था ?

इसी से जुड़ा एक और सवाल है। वेंगसरक पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने यह करार तोड़ा इसके पहले गावस्कर और कपिलदेव भी अप कप्तानी के दौरान अखबारों में बाकायदा लिखते हैं। फिर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं क गयी ? आखिर वेंगसरकर पर ही यह बिजली क गिरायी गयी ? क्या इसलिए कि वेंगसरकर उन मुकाबले कमजोर कप्तान थे ? आखिर दो कप्ता

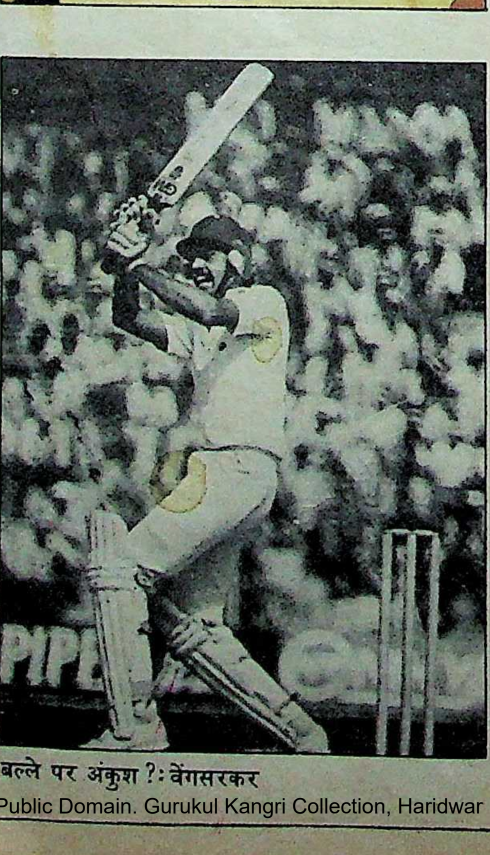

बल्ले पर अंकुश ?: वेंगसरकर

के लिए अलग-अलग दंड व्यवस्था क्यों ? वेंगसरकर काफी हद तक सीमा में रहकर लिखते थे, जबकि गावस्कर खुलकर लिखते थे। केवल खेल के बारे में ही नहीं, बोर्ड की नीतियों के बारे में भी। मगर बोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शायद गावस्कर जैसे बड़े खिलाड़ी से टकराने का उसमें साहस नहीं था और इसीलिए उसने अपना सारा गुस्सा एक कमजोर कप्तान यानी वेंगसरकर पर उतारा है।

बोर्ड ने गावस्कर के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया है और कार्रवाई करने की बात कही है। उसकी शिकायत है कि गावस्कर ने कई मर्तबा बोर्ड पर उंगलियां उठायी थीं। रिलायंस कप के पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर को गावस्कर द्वारा 'मजाक' बताये जाने से (जो कि था भी) बोर्ड खास तौर पर खफा है। लेकिन अब बोर्ड उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता और दूसरे अगर वह ऐसा कुछ करता भी है, तो यह बेवकूफी ही कहलायेगी, क्योंकि अब वह क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और एक महान खिलाड़ी के ऊपर उसके संन्यास लेने के बाद कीचड़ उछालना ठीक नहीं होगा।

बोर्ड ने अपनी इस कार्रवाई को अनुशासन से भी जोड़कर जायज ठहराने की कोशिश की है। उसके खयाल में वेंगसरकर ने अनुशासन भंग किया है और उन्हें दंडित न किया जाता, तो इससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता। इस 'बहाने' पर इतना कहना काफी होगा कि ऐसे किसी भी कानून का, जो खेल और खिलाड़ी के खिलाफ जाता हो, तोड़ा जाना ही ठीक है, भले ही उसमें अनुशासनहीनता की ही झलक क्यों न मिलती हो। बोर्ड कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसके बनाये हर गलत-सही कानून का पालन हर सूरत में होना ही चाहिए। हां, यदि ऐसा होता कि ऐसा ही करार वेस्टइंडीज टीम के साथ भी होता और रिचर्ड्स द्वारा उसके पालन करने के बावजूद वेंगसरकर उल्लंघन करते, तो निश्चय ही वह इस सजा के लायक होते।

कड़ी कार्रवाई : इस सबके बावजूद यदि बोर्ड की नजर में वेंगसरकर दोषी थे ही, तो उन पर केवल जुर्माना किया जा सकता था। छह माह तक प्रतिबंध और दस हजार रुपए का जुर्माना बहुत बड़ी सजा है। खास तौर पर प्रतिबंध लगाने की बात समझ से परे है। एक-डेढ़ महीने पहले ही इंग्लैंड-पाक श्रृंखला में माइक गैटिंग और अंपायर शकूर राणा के बीच गाली-गलौज के बाद श्रृंखला ही खतरे में पड़ गयी थी। निश्चित रूप से यह विवाद वेंगसरकर-प्रकरण से ज्यादा गंभीर था, लेकिन गैटिंग को माफी मांगने के अलावा और क्या कहा गया ? यहां तक कि अंग्रेज क्रिकेट अधिकारी उनके साथ थे और अब भी उनकी कप्तानी बरकरार है। इस तरह साफ है कि एक मामूली से अपराध के लिए वेंगसरकर को बहुत बड़ी सजा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कहीं बोर्ड ने ऐसा अपना वर्चस्व और तानाशाही स्थापित करने की कोशिश में तो नहीं किया ?

—मुकेश कुमार

गावस्कर ने कई मर्तबा बोर्ड पर उंगलियां उठायी थीं। रिलायंस कप के पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर को गावस्कर द्वारा 'मजाक' बताये जाने से (जो कि था भी) बोर्ड खास तौर पर खफा है। लेकिन अब बोर्ड उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता और दूसरे अगर वह ऐसे कुछ करता भी है, तो यह बेवकूफी ही कहलायेगी, क्योंकि अब वह क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और एक महान खिलाड़ी के ऊपर उसके संन्यास लेने के बाद कीचड़ उछालना ठीक नहीं होगा।

कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब
चुटकी पान मसाला खाईऐ जनाब
सौंफ इलायची छुआरे वाला
चुटकी
पान मसाला
Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"
Chutki
CHUTKI
चुटकी
چٹکی
சுட்க்கி
के० के० कार्यालय का उत्कृष्ट उत्पादन

सुब्रत मुखर्जी

नेता से अभिनेता

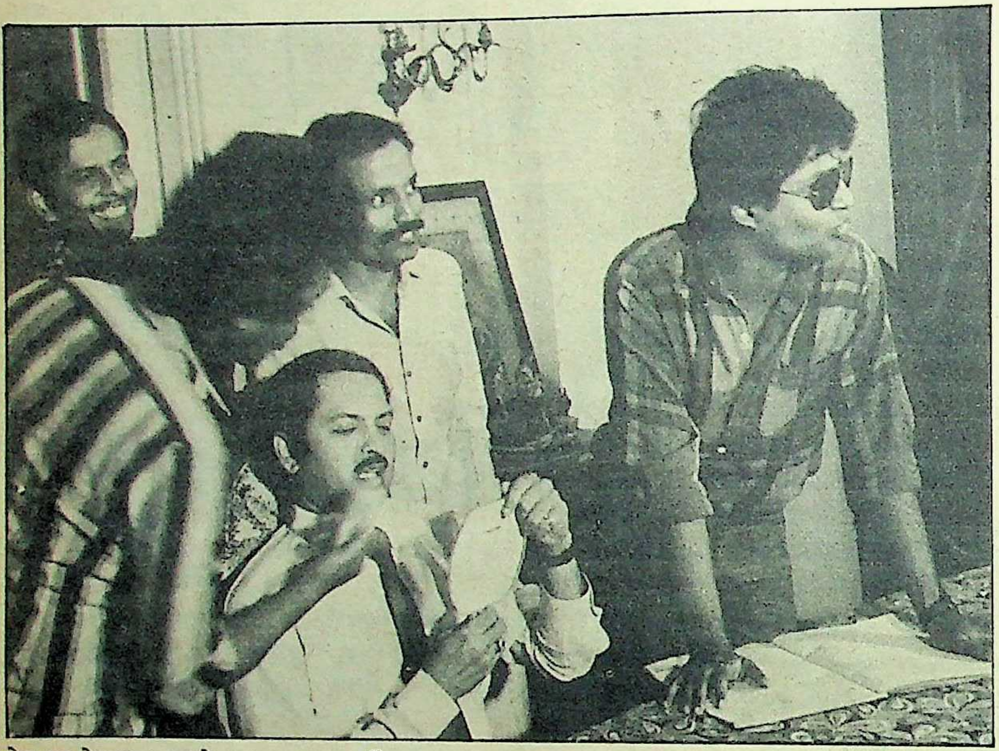

सेट पर मेकअप करवाते हुए : सुब्रत मुखर्जी

फिल्मों के रुपहले-सुनहले परदे से राजनीतिक मंच पर आना भारतीय संदर्भों में नया नहीं है, लेकिन राजनीति से फिल्मों की ओर मुड़ने के कम ही उदाहरण हैं। जनता सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण के बाद पश्चिम बंगाल के जुझारू और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सुब्रत मुखर्जी युवा फिल्म निदेशक अग्निदेव चट्टोपाध्याय की टी०वी० फिल्म 'चौधरी फार्मास्युटिकल्स' में नायक की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ हीरोइन के रूप में हैं, बंगला-बंबइया फिल्मों की ग्लैमर गर्ल मुनमुन सेन। सुब्रत मुखर्जी में नेता से अभिनेता बनने की ललक क्यों पैदा हुई ?

कलकत्ता दूरदर्शन के लिए निर्माणाधीन 'चौधरी फार्मास्युटिकल्स' सीरियल ने इस समय फिल्म-प्रेमियों में जबर्दस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि इसकी प्रधानभूमिका निभा रहे हैं—पश्चिम बंगाल की राजनीति के विवादास्पद व्यक्तित्व सुब्रत मुखर्जी। राजनीति के आंगन से निकलकर अभिनय के क्षेत्र में सुब्रत बाबू का यह प्रथम प्रवेश है। सिर्फ सुब्रत मुखर्जी के लिए ही नहीं, शायद पश्चिम बंगाल के किसी भी नेता के लिए फिल्म में अभिनय करने की यह पहली घटना है।

इस टीवी फिल्म में अभिनय करने से पहले सुब्रत बाबू ने बहुत सोच-विचार किया है। इसमें समय भी काफी लगा है। शुरू से आखिर तक पटकथा को पढ़ने के बाद जब वह उनको पसंद आयी, तभी उन्होंने निदेशक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। सुब्रत बाबू का कहना है, "चौधरी फार्मास्युटिकल्स' फिल्म की कथा के सामाजिक पहलू ने मुझे बड़ा आकृष्ट किया है। राजनीतिक मंच पर खड़े होकर समाज के जिन अशुभ लक्षणों के विरुद्ध आवाज उठाता हूं, इस कहानी में वैसे ही एक लक्षण को रेखांकित किया गया है। नाटक या फिल्म के माध्यम से कुछ कहने पर वह कथन बहुत जल्दी जनता तक पहुंच जाता है। यही सब सोचकर मैं इस सीरियल में अभिनय करने के लिए सहमत हुआ हूं।"

कथा-क्रम : सुब्रत बाबू जब स्वयं इस फिल्म की कहानी से इतने प्रभावित हुए हैं, तब जन साधारण में उसके बारे में जानने की उत्सुकता पैदा होना स्वाभाविक है। इस फिल्म-कथा के केंद्र में दवा बनानेवाली एक कंपनी है— 'चौधरी फार्मास्युटिकल्स'। चौधरी परिवार के स्वामी विक्रम चौधरी की रहस्यमय मृत्यु से कथा शुरू होती है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी सुंदरी पुत्री रूपा इंग्लैंड से स्वदेश लौटी। स्वाभाविक रूप से रूपा ने पिता के व्यवसाय को चलाने का भार संभाला। बारह वर्ष विदेश में बिताकर घर लौटने के बाद रूपा अच्छी तरह समझ गयी कि परिवार का हर सदस्य बड़ी चालाकी से उससे दूर रहने लगा है। बड़ा भाई अजय व्यवसाय पर अपना एकाधिकार जमाने के फिराक में है, तो दूसरा भाई इस दिशा में एकदम उदासीन। फिर रूपा के तीसरे भाई अमित का इंदु नाम की लडकी से प्रेम, इस प्रेम-संबंध के कारण इंदु का गर्भवती होना, पारिवारिक चिकित्सक डा० बख्शी की सहायता से इंदु की हत्या की साजिश, अमित के विवाह में मां सुजाता देवी की आपत्ति, दुर्घटना में अमित की मृत्यु जैसे घटनाक्रम के साथ ही साथ दवा कंपनी का काम संभालते हुए रूपा का दीपक चटर्जी से परिचय हुआ। परिचय भी प्रेम में बदल गया। एक तरफ प्रेम, तो दूसरी तरफ दवा का व्यवसाय। अंत तक रूपा यह भी समझ गयी कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होने जा रही है। पारिवारिक चिकित्सक डा० बख्शी का आचरण भी संदेहजनक लगने लगा। सिर्फ एक हफ्ते के लिए दीपक रिसर्च सेंटर में काम करने गया, तो अस्वाभाविक स्थिति में लौट आया। अब रूपा के सामने गुप्त साजिश की रूपरेखा स्पष्ट हो गयी। फिर संयुक्त प्रयास से रूपा और दीपक उस साजिश का जाल काटकर बाहर निकले। निर्माणाधीन इस टीवी फिल्म की यही संक्षिप्त कथा है।

इस कथा में ड्रग के बढ़ते प्रभाव को ही नहीं, दवा कंपनियों द्वारा अपनाये जा रहे असाधु उपाय को भी स्पष्ट रेखांकित करने का प्रयास इसके लेखक तथा निदेशक अग्निदेव चट्टोपाध्याय ने किया है। चट्टोपाध्याय ने यह भी दावा किया है कि 'चौधरी फार्मास्युटिकल्स' ही पहला मल्टी-स्टार बंगला टीवी सीरियल है।

पात्र : इस सीरियल में दीपक चटर्जी की भूमिका में सुब्रत मुखर्जी और रूपा की भूमिका में मुनमुन सेन हैं। अन्य भूमिकाओं में अभिनय कर रहे हैं— सत्यजित राय की 'तीन कन्याएं' की एक कन्या सुमिता सान्याल, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त ममता शंकर, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म निदेशक गौतम घोष, निदेशक तरुण मजूमदार की नयी आविष्कृति नैना दास, बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जार्ज बेकर और देवाशिस घोष आदि। अगली मई से इस सीरियल को छोटे परदे पर दिखाने का लक्ष्य लेकर पूरी रफ्तार से इसका काम किया जा रहा है। कलकत्ता दूरदर्शन ने इस बीच १३ एपीसोडों की स्वीकृति भी दे दी है।

प्रतिक्रियाएं : जबर्दस्त जुझारू नेता सुब्रत मुखर्जी तो इस सीरियल में अपना अभिनय सचमुच सीरियस होकर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी राजनीति के क्षेत्र में इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही निराशाजनक है। सुब्रत मुखर्जी के प्रतिपक्षी के रूप में परिचित कांग्रेसी विधायक सोमेन मित्र ने सवाल किया है, "कभी सुब्रत बाबू ही कहा करते थे कि पार्टटाइम राजनीति करनेवाले लोग पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन अब फिल्म में काम करना शुरू कर उनके लिए भी तो पार्टी को

पूरा समय देना संभव नहीं होगा। फिर क्या सुब्रत बाबू जैसे कुशल और सीरियस नेता भी अंत तक पार्टटाइमर बनने जा रहे हैं?''

कांग्रेस के दूसरे नेता हैं साधन पांडे। विधान सभा को हिलाकर रखनेवाले विधायक के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। जुझारू श्रमिक नेता के रूप में राजनीति में आने और मंत्रिपद पर प्रतिष्ठित होनेवाले पांडे ने सुब्रत मुखर्जी द्वारा फिल्म में अभिनय करने के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, ''मैदान के सभामंच पर बार-बार आकर भी जिनकी आस पूरी नहीं हुई, अब वह चेहरे पर रंग पोतकर नायिका के साथ अभिनय किये बिना कैसे रह सकते हैं? राजनीति में बहुत दिन हो गये। अब उनके लिए नायक बनना ठीक रहेगा। ज्यादा उम्र हो जाने पर तो नायक नहीं बन सकेंगे।''

रोमांटिक युगल : बायें से मुनमुन सेन और सुब्रत मुखर्जी

सुब्रत बाबू फिल्म में अभिनय करने लगे, तो शुरू में कांग्रेसी नेताओं ने उसे हंसी-मजाक में लिया, लेकिन अब मामला गंभीर हो चला है। पश्चिम बंगाल मे प्रथम पंक्ति के अधिकांश कांग्रेसी नेता सुब्रत बाबू के निर्णय को अच्छे मन से नहीं ले पा रहे हैं। एक वर्ग ने सीधे विभिन्न माध्यमों से अपना विचार व्यक्त किया है, तो दूसरे वर्ग ने अपनी टीका-टिप्पणी को जनता के सामने नहीं रखा, लेकिन उनके रंग-ढंग से लगता है कि सुब्रत बाबू के निर्णय से वे किसी तरह प्रसन्न नहीं हैं।

उठते सवाल : अब प्रसंगत: यह सवाल उठा है कि फिल्म में अभिनय करने का प्रभाव कांग्रेसी नेता सुब्रत मुखर्जी के राजनीतिक जीवन पर कैसा पड़ेगा या कुछ भी नहीं पड़ेगा? जानकार लोगों का खयाल है कि सुब्रत बाबू के राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। सुब्रत बाबू को अभिनय का पूर्व अनुभव नहीं है। राजनीति की बदौलत वह परिचित हुए हैं। उसी परिचय के बल पर उनको इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला है। अब इस अभिनय को केंद्र में रख कर उन्हीं के साथी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से व्यंग्य और विवाद का जो बवाल खड़ा किया गया है, भविष्य में उसके प्रबल आरोप के रूप में सामने आने की संभावना है। लेकिन सुब्रत बाबू स्वयं ऐसी संभावना को स्वीकार नहीं करते।

अभिनय के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुखर्जी ने प्रतिवेदक को बताया— अभिनेता के रूप में कैमरे के सामने खड़े होने पर मैं कांग्रेसी नहीं रहूंगा या मैं अपने आदर्श से दूर हट जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। फिर अभिनय करने पर मेरा राजनीतिक कैरियर चौपट होगा और न करने पर नहीं, यह किसने कहा है? एम०जी० रामचंद्रन, एन०टी० रामाराव, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त आदि फिल्मी इमेज लेकर राजनीति में आये हैं। फिर राजनीति करने लगे हैं, तो उनकी फिल्मी इमेज खतम हो गयी है— क्या ऐसा अंदेशा दिखायी पड़ने लगा है? अगर ऐसा नहीं है, तो राजनीति से अभिनय के क्षेत्र में आने पर मेरे राजनीतिक इमेज नष्ट होने की क्यों आशंका है? फिर अपने राजनीतिक साथियों द्वारा की जा रही आलोचना के बारे में यही कहूंगा कि विवादित होना मुझे पसंद है। यह अभिनय मेरे लिए थ्रिलिंग चैलेंज है। लेकिन मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर अभिनय करने नहीं जा रहा हूं। अभिनय के लिए चाहे काम का दबाव जितना आये, महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता पर मैं हमेशा तैयार रहूंगा। फिर जीवन तो एक ही है। थोड़ा-बहुत अभिनय करना क्या बुरा है? इसका यह भी मतलब नहीं कि मैंने अभिनय को कभी हलका समझा है। मुफ्त में काम करने पर कहीं निष्ठा का अभाव हो, इसलिए पैसा भी ले रहा हूं। डायटिंग कर पांच किलो वजन भी घटाया है। सबेरे जागिंग भी करता हूं। फुर्सत मिलते ही स्क्रिप्ट पढ़ता हूं। देर तक सूट-टाई पहनकर बैठे रहने की भी आदत डालने लगा हूं। निदेशक के हाथों में अपने को पूरी तरह सौंप देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगा हूं जो किसी राजनीतिक नेता के लिए लगभग असंभव है।

एन०टी०आर०, एम०जी०आर०, सुनील दत्त या अमिताभ बच्चन का उदाहरण सुब्रत बाबू के लिए उलटा बैठता है, क्योंकि सुब्रत बाबू राजनीति से फिल्म में आये, तो ये लोग फिल्म से राजनीति में आये हैं। फिर भी इन उदाहरणों का और पश्चिम बंगाल के प्रथम राजनीतिक नेता के रूप में फिल्म में काम करने का मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह पूछने पर सुब्रत बाबू ने कहा, ''इन उदाहरणों का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं है और न इस संबंध में कुछ सोचना चाहता हूं। इस समय सिर्फ यही चिंता है कि मन से तमाम दूसरी बातें निकालकर 'दीपक' से एकात्म हो जाऊं। इतना हो गया, तो बहुत है। फिर, यही प्रथम है और यही अंतिम। इसके बाद अभिनय नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है।''

मुनमुन उवाच : 'चौधरी फार्मास्यूटिकल्स' फिल्म की नायिका मुनमुन सेन का कहना है कि मेरे साथ नायक के रूप में सुब्रत मुखर्जी अभिनय नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगी। इस प्रसंग में एक प्रश्न के उत्तर में मुखर्जी ने बताया, ''मुनमुन सेन के साथ अभिनय कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन में कोई खास फीलिंग नहीं है। जब अभिनय करना है तब तो किसी के साथ करना ही पड़ेगा। यह संयोग है कि मुनमुन सेन अभिनय कर रही है। इसके अलावा मैं मुनमुन को बहुत दिनों से जानता हूं। अब रही झिझक और हिचक की बात, तो राजनीति करते हुए वह बहुत पहले खतम हो चुकी है। नायक सुब्रत मुखर्जी के साथ अभिनय करने की प्रतिक्रिया के बारे में नायिका मुनमुन सेन ने बताया, ''बहुतों के साथ अभिनय किया है। अब एक राजनीतिक नेता नायक के रूप में हैं, तो नयापन क्यों न महसूस हो? फिर सुब्रत दा को मैं पहले से जानती हूं। अब उनकी जनप्रियता को एक दूसरे ही माध्यम से देख पाऊंगी। इसका मजा ही अलग है।'' फिल्म से राजनीति में आने का यह क्रम अब नहीं रुक सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिल्म से राजनीति को जोड़ने की परंपरा नहीं थी। फिर भी पिछले विधान सभा चुनाव में रहस्यमयी सुचित्रा देवी के फिल्मी इमेज को सामने रखकर उनको बोलपुर क्षेत्र से इंका प्रत्याशी बनाने का सुझाव वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी की तरफ से आया था, लेकिन उस सुझाव का कार्यान्वयन नहीं हुआ। अब क्या सुचित्रा देवी की पुत्री मुनमुन को वैसे किसी लक्ष्य की तरफ ले चलने का प्रयास हो रहा है? खैर, मुनमुन प्रसंग कुछ भी हो, जुझारू कांग्रेसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में फिल्म और राजनीति को निकट लाकर एक नया रुझान पैदा किया, लेकिन एन०टी०आर० और एम०जी०आर० के विपरीत पथ पर चलकर। हालांकि अब सफलता दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

—गुरुप्रसाद महांति

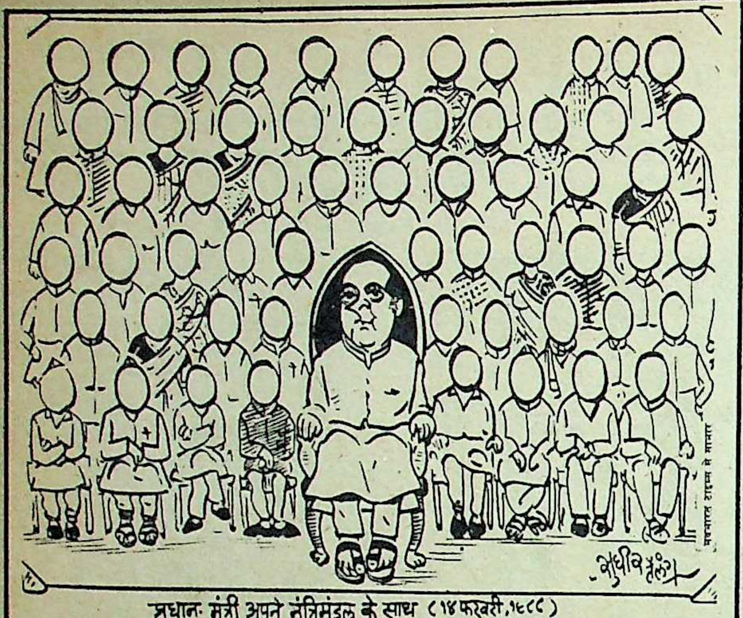
नवभारत टाइम्स से साभार
सुधीर तैलंग

प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ (१४ फरवरी,१९८८)

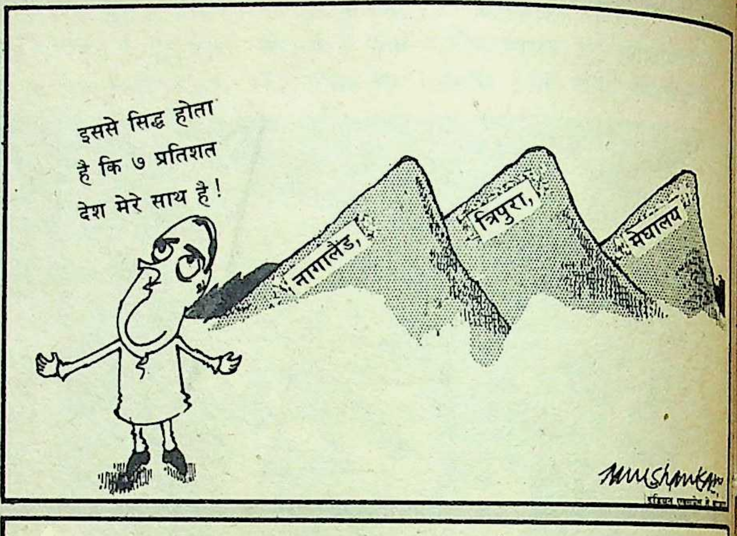
इससे सिद्ध होता है कि ७ प्रतिशत देश मेरे साथ है!
नागालैंड,
त्रिपुरा,
मेघालय
Ravishankar
इंडियन एक्सप्रेस से साभार

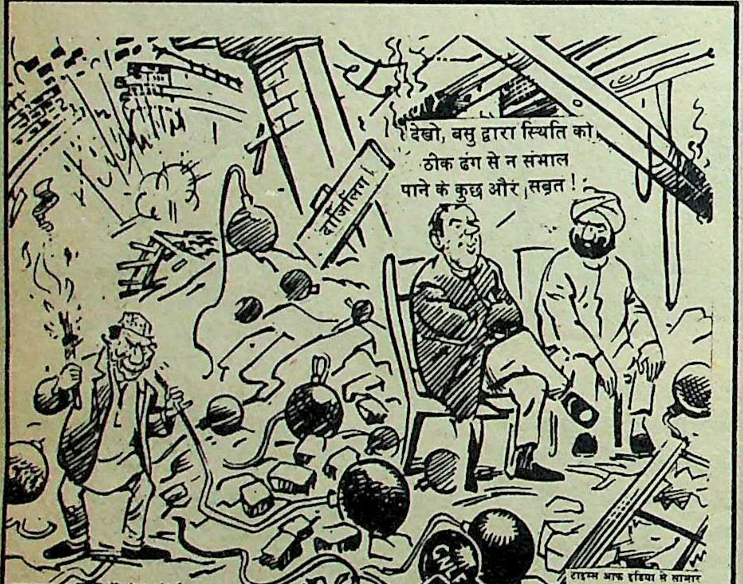
देखो, बसु द्वारा स्थिति को ठीक ढंग से न संभाल पाने के कुछ और सबूत!
दार्जिलिंग
टाइम्स आफ इंडिया से साभार
व्यंग्यकार: आर०के० लक्ष्मण

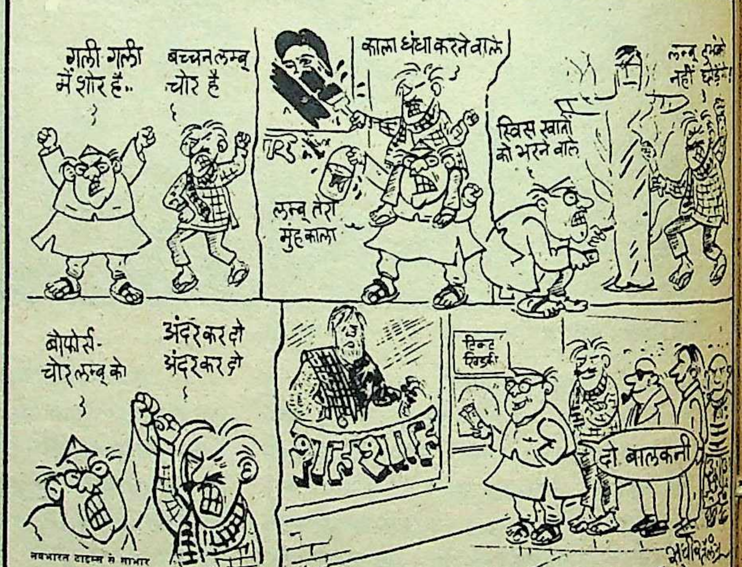
गली गली में शोर है..
बच्चन लम्बू चोर है
काला धंधा करने वाले
लम्बू तेरा मुंह काला
स्विस खाते को भरने वाले
लम्बू तुझको नहीं छोड़ेंगे!
बोफोर्स-चोर लम्बू को
अंदर कर दो अंदर कर दो
शहंशाह
टिकट खिड़की
दो बालकनी
नवभारत टाइम्स से साभार
सुधीर तैलंग

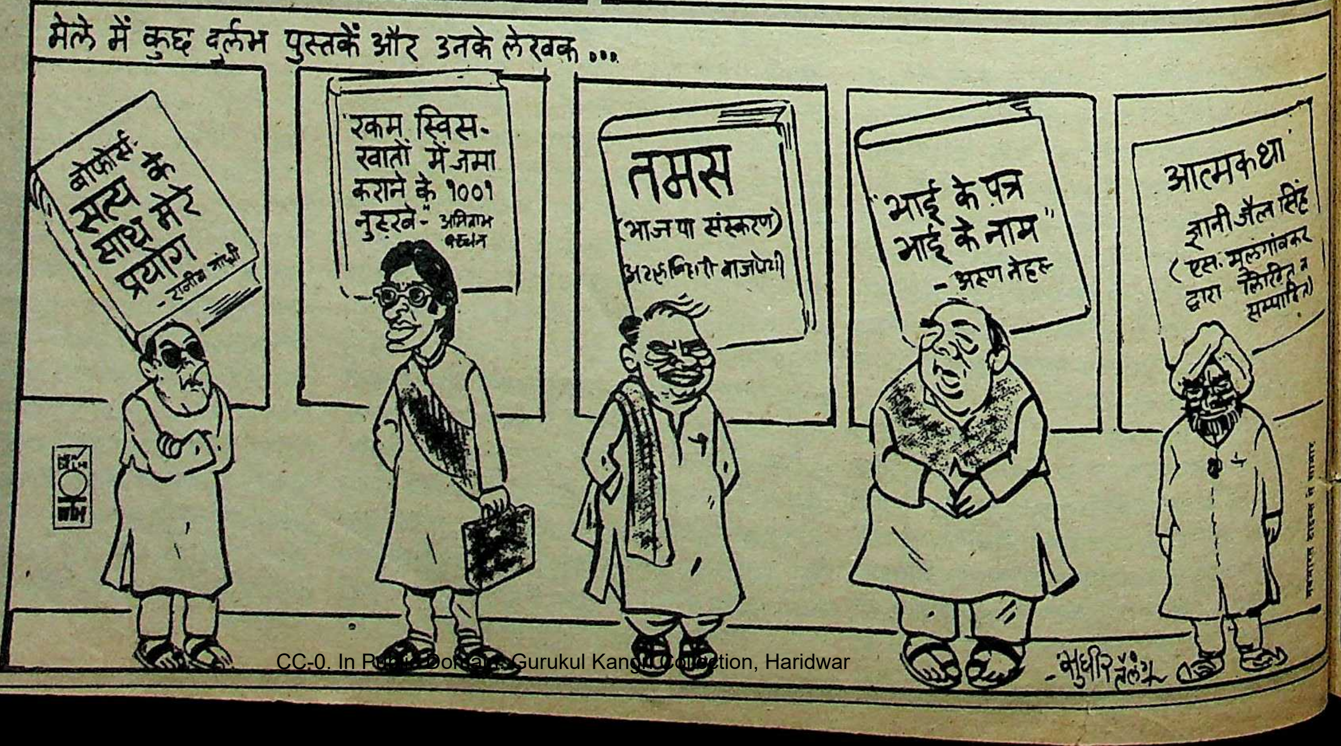
मेले में कुछ दुर्लभ पुस्तकें और उनके लेखक ...
बोफोर्स के सत्य के साथ मेरे प्रयोग - राजीव गांधी
रकम स्विस-खातों में जमा कराने के 1001 नुस्खे - अमिताभ बच्चन
तमस (भाजपा संस्करण) अटल बिहारी बाजपेयी
"भाई के पत्र भाई के नाम" - अरुण नेहरू
आत्मकथा ज्ञानी जैल सिंह (एस. मूलगांवकर द्वारा लिखित व सम्पादित)
नवभारत टाइम्स से साभार
सुधीर तैलंग

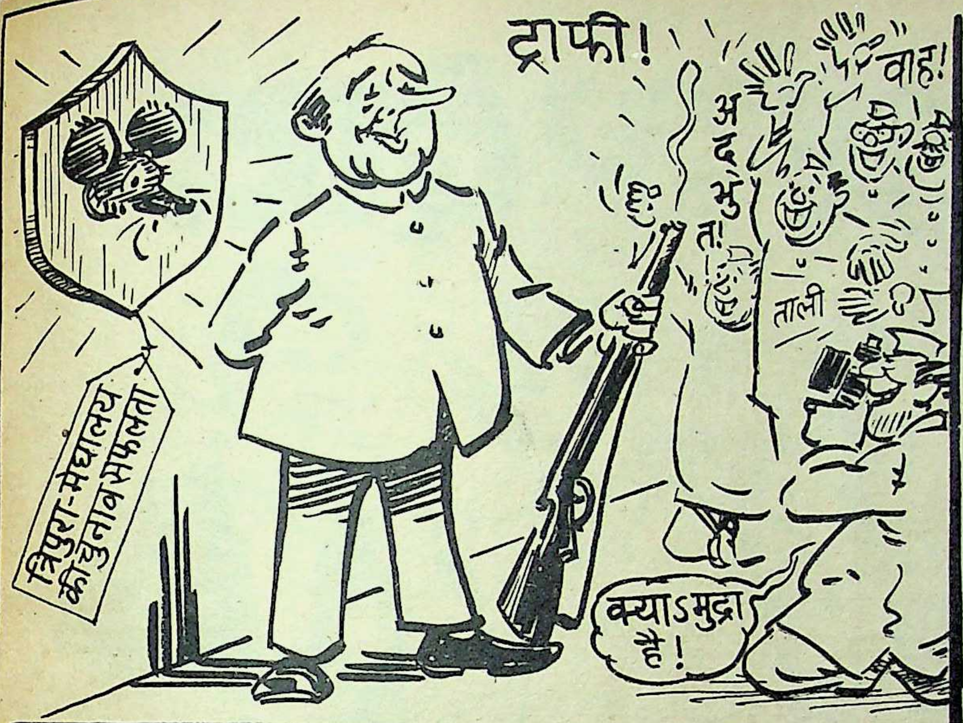
ट्राफी!
वाह!
अद्भुत!
ताली
त्रिपुरा-मेघालय की चुनाव सफलता
क्याऽ मुद्रा है!

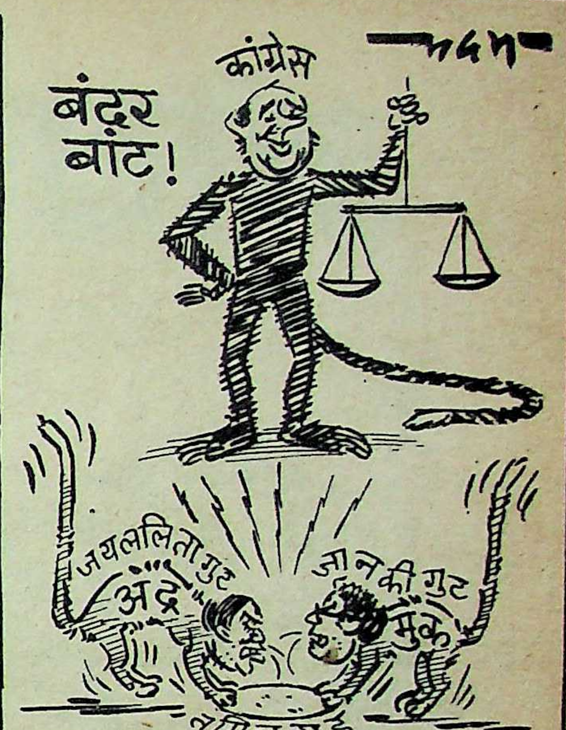
बंदर बांट!
कांग्रेस
जयललिता गुट
अन्द्रे
जानकी गुट
मुक
तमिल नाडु

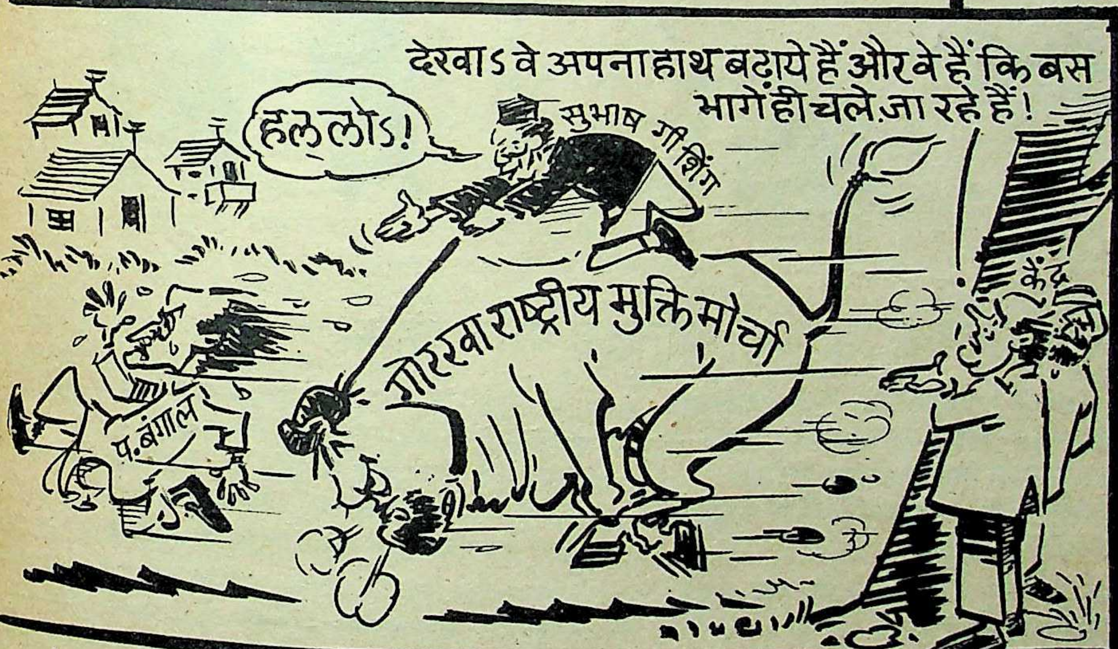
देखाऽ वे अपना हाथ बढ़ाये हैं और वे हैं कि बस भागे ही चले जा रहे हैं!
हललोऽ!
सुभाष घीसिंग
गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा
प. बंगाल
केंद्र

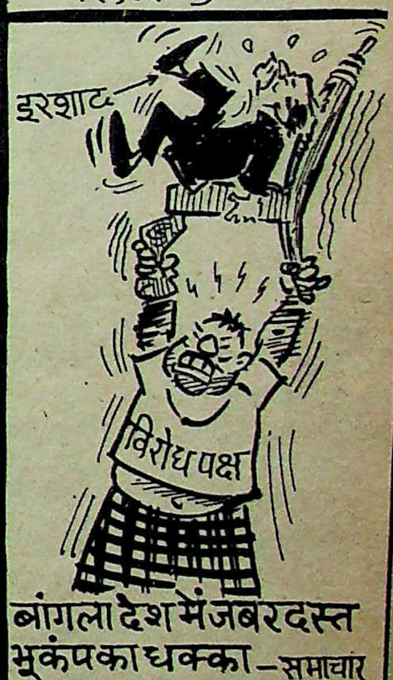
इरशाद
विरोध पक्ष

बांगला देश में जबरदस्त भूकंप का धक्का —समाचार

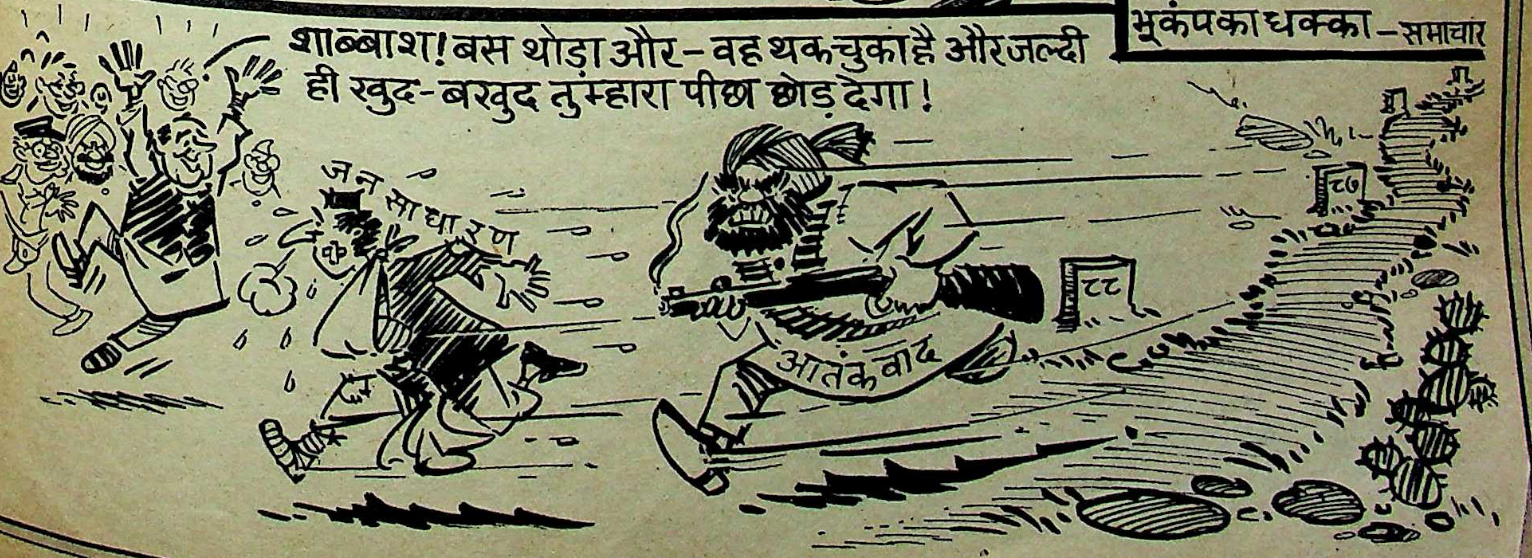
शाबाश! बस थोड़ा और— वह थक चुका है और जल्दी ही खुद-बखुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगा!
जन साधारण
आतंकवाद

जीवन अक्षय

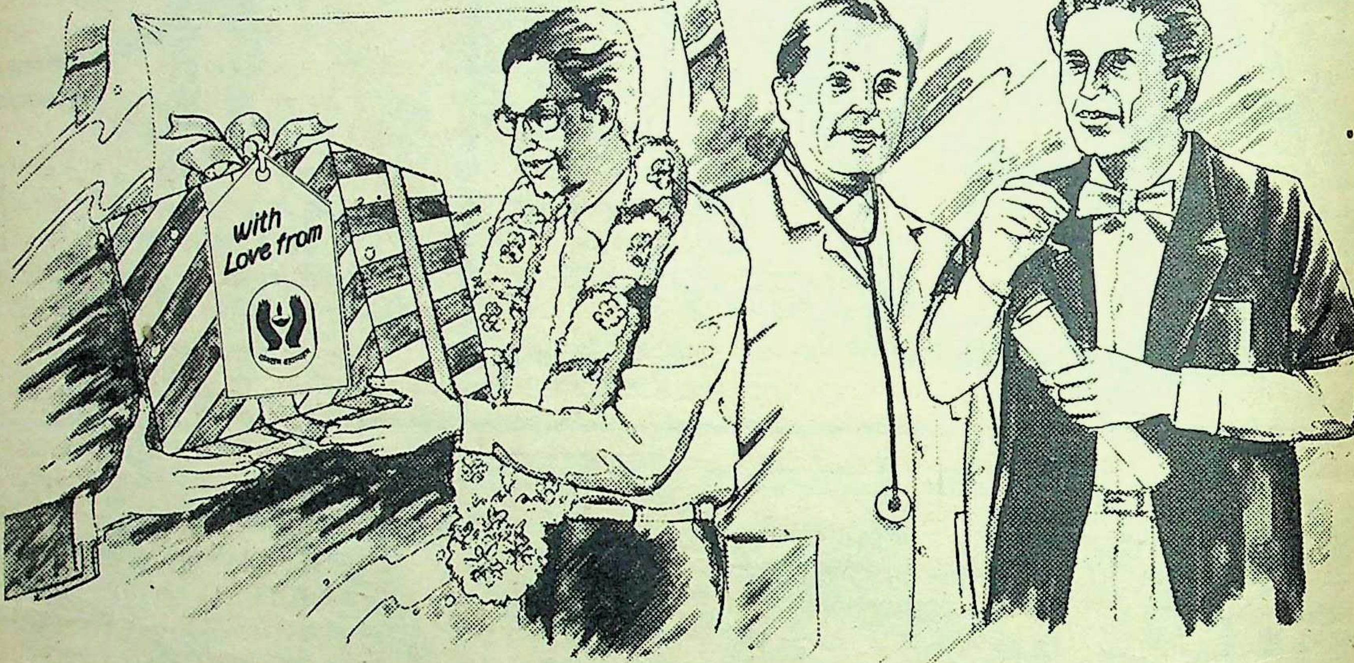

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना

हाल ही में एल आई सी ने किशोर/जवान और मध्यम आयु के लोगों के लिए 'जीवनधारा' पेंशन योजना आरंभ की थी ताकि वे कुछ अवधि में सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत बना सकें.

अब एल आई सी ५० वर्ष और उससे अधिक की आयु वालों के लिए आरंभ कर रही है

'जीवन अक्षय' योजना

जीवन अक्षय योजना किसान, मज़दूर, नौकरी-पेशे वाले लोगों, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, व्यापारियों अथवा व्यवसाइयों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है. कामकाजी व्यस्त जीवन से छुट्टी पाने के बाद हर एक को किसी आर्थिक सहारे की ज़रूरत होती है, ख़ासकर अब, जब जीवन यात्रा लम्बी हो गई है. एक ही भुगतान से ख़रीदी जाने वाली 'जीवन अक्षय' एन्यूटी (वार्षिक) योजना इस ज़रूरत को हर तरह से पूरा करती है.

सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले फ़ायदे जैसे कि प्राविडेन्ड फ़ण्ड और ग्रेच्युटी तथा परिपक्वता पर मिलने वाली जीवन बीमा की राशि को, आकर्षक, सुरक्षित और नियमित आमदनी प्राप्त करने के लिए, जीवन अक्षय योजना में बखूबी लगाया जा सकता है.

रु. १०,०००/- के एक ही प्रीमियम से आप रु. १००/- प्रतिमाह पेंशन पा सकेंगे.

इसके अलावा पेंशनर की मृत्यु पर उसके मनोनीत को जी आई एस (ग्रॉस इन्श्योरेंस सम) (बीमा की राशि) के साथ साथ अन्तिम **जीवन अक्षय बोनस** भी दिया जाएगा.

अपने जीवन के अन्तिम दिन आप आनन्द और विश्वास से बिता सकें यही हैं 'जीवन अक्षय' का उद्देश्य.

अधिक जानकारी के लिए अपनी नज़दीकी एल आई सी शाखा अथवा अपने एजेंट से सम्पर्क करिए.

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम - जनता की सेवा में.

EP/LIC-90/88 HIN

श्रीलंका

एक और समझौता समर्थक की हत्या

श्रीलंका के लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और वामपंथी दल श्रीलंका महाजना पार्टी (एसएलएमपी) के नेता ४३ वर्षीय विजय कुमारणतुंगा की एक सिहल उग्रवादी गुट के कुछ सदस्यों ने गत १६ फरवरी को हत्या कर दी। कुमारणतुंगा भारत-श्रीलंका समझौते के कट्टर समर्थक थे और उग्रवादियों की खुलकर निंदा करने में नहीं हिचकते थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री सिरीमाओ भंडारनायके के दामाद थे। हत्या से एक दिन पहले ही उन्होंने सिंहली उग्रवादी गुट जे०वी०पी० (जनता विमुक्ति पेरामुना) की जमकर भर्त्सना की थी। श्रीलंका में दो महीनें के अंदर यह दूसरे बड़े नेता की हत्या है। गत २३ दिसंबर को सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हर्ष अभयवर्धन की हत्या भी सिंहली उग्रवादियों ने कर दी थी।

कुमारणतुंगा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सिरीमाओ भंडारनायके की पुत्री चंद्रिका से शादी हो जाने के बाद की। वह सिरीमाओ की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) में शामिल हो गये थे। कुछ समय बाद अपने समाजवादी रुझान के कारण पार्टी के ही वामपंथी विचारों वाले नेताओं के साथ हो गये और सिरीमाओ के धुर दक्षिणपंथी पुत्र अनुरा से उनका विरोध बढ़ता गया। यह विरोध इतना बढ़ा कि १९८४ में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वामपंथी विचारधारा वाली श्रीलंका महाजना पार्टी (एसएलएमपी) का गठन कर लिया।

ऐसे समय में जब पूरा देश हिंसा और उग्रवाद की चपेट में हो, किसी नेता का खुलकर उग्रवाद का विरोध करना निश्चय ही साहस का काम कहा जायेगा, और कुमारणतुंगा ने यही किया। उन्होंने सिंहली और तमिल जाति की संकुचित सोच से हटकर अपनी पार्टी की दिशा निर्धारित की। अपने दल में उन्होंने तमिल और सिंहली दोनों ही पक्षों की धर्मनिरपेक्ष ताकतों को शामिल किया। वामपंथी तमिल उग्रवादियों को भी उन्होंने एक करने की कोशिश की। अपने इन्हीं विचारों के कारण सिंहली होते हुए भी वह तमिलों में भी काफी लोकप्रिय हो गये थे।

कुमारणतुंगा प्रतिबद्ध समाजवादी थे और सिंहली उग्रवादी गुटों का खुलकर विरोध करते थे। 'जेवीपी' उनके शब्दों में, "एक उग्रवादी संगठन है, जिसे न तो जनता का समर्थन प्राप्त है और न ही उसकी कोई ताकत है। वह केवल अव्यवस्था फैला सकता है।" उसकी पार्टी को मुख्य रूप से १८ से ३५ वर्ष के युवा लोगों का समर्थन प्राप्त था, जो कि देश के ६५ प्रतिशत मतदाता हैं। इस तरह उन्हें पूरा यकीन था कि वाममोर्चा इस बार सत्ता हासिल कर लेगा। हाल में चार प्रमुख दलों ने मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष वामपंथी पार्टियों का गठबंधन यूनाइटेड सोशलिस्ट रिलायंस बनाया था। इसमें तमिल छापामारों के दलों को भी शामिल होने का आग्रह किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि यह संयुक्त मोर्चा कुमारणतुंगा को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनायेगा।

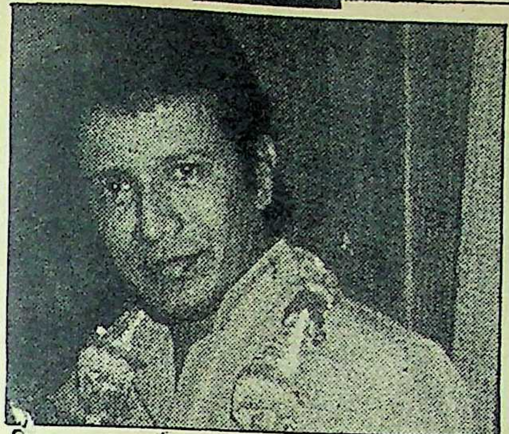
विजय कुमारणतुंगा

श्री विजय ने राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जून १९८६ और जनवरी १९८७ की मद्रास यात्रा के दौरान किया। देश को जातीय समस्या से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ये यात्राएं कीं तथा लिट्टे और तुल्फ दोनों तमिल गुटों के नेताओं से मिलकर समझौते का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्हें काफी समय से हत्या की धमकियां मिल रही थीं, मगर अपने विचार उन्होंने कभी नहीं बदले। पिछले दिनों एक कम्युनिस्ट नेता की हत्या के बाद उन्होंने कहा था, "हम समझौते की रक्षा के लिए जान तक की बाजी लगा देंगे।"

कुमारणतुंगा की मृत्यु से श्रीलंका के वाममोर्चे को खासा नुकसान हुआ है। १९४७ में श्रीलंका को आजादी मिलने के समय वह सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बाद में उसका प्रभाव घटता गया। उनके प्रयासों से इस मोर्चे में फिर जान आ गयी थी।

सिंहली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उन्होंने १९६९ के बाद १०० से भी अधिक फिल्मों में काम किया था।

आस्ट्रिया

वाल्डहाइम अभी इस्तीफा नहीं देंगे

आस्ट्रिया के राष्ट्रपति कुर्ट वाल्डहाइम पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। आस्ट्रियाई सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय इतिहासकारों का एक आयोग डा० वाल्डहाइम पर लगे आरोपों की जांच के लिए बिठाया गया था। इस आयोग की रपट आने के बाद नये सिरे से हंगामा शुरू हो गया है। डा० वाल्डहाइम पर ये आरोप लगाये जाते रहे हैं कि उन्होंने नात्सी सेना में जूनियर लेफ्टिनेंट की हैसियत से १९४४ में ग्रीस के हजारों यहूदियों को हत्या-शिविरों में भेजने की कार्रवाई में हिस्सा लिया था और युगोस्लाविया के देशभक्तों को खतम करने में भी उन्होंने भूमिका निभायी थी।

आयोग की रपट ने डा० वाल्डहाइम को न तो पूरी तरह दोषी बताया है और न ही आरोप से बरी किया है। रपट में कहा गया है कि यद्यपि वाल्डहाइम ने उक्त मामलों में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभायी थी, मगर फिर भी वह उस व्यवस्था के एक अंग तो थे ही। डा० वाल्डहाइम यह बात तो स्वीकारते हैं कि वह नात्सी सेना में अफसर थे, मगर इतने ही को वह अपराध नहीं मानते। आयोग की रपट पर उनका कहना है कि किसी कार्रवाई का अंग होना और खुद कार्रवाई करना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

पिछले साल आस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी यह विवाद उठा था। डा० वाल्डहाइम भी एक उम्मीदवार थे और उनके विरोधियों ने उनकी छवि पर लगे इस दाग को खूब उछाला था। यहां तक कि अमरीका और ब्रिटेन के सूचना माध्यम भी उनके खिलाफ अभियान में जुट गये थे, लेकिन इस सबके बावजूद उन्होंने चुनाव जीत लिया था। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी विवाद जारी रहा, फलस्वरूप आस्ट्रियाई सरकार ने एक आयोग बिठा दिया था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो वाल्डहाइम की आलोचना काफी समय से हो रही है, मगर आयोग की रपट आने के बाद अब उनके देश में ही विरोध जोर पकड़ने लगा है। चांसलर फ्रेंज ब्रेनित्जकी ने तो इस्तीफा तक देने की धमकी दे डाली है। उनका कहना है कि इस विवाद से देश की छवि खराब हो रही है और वाल्डहाइम को इस विवाद के निपटाने के लिए जल्दी से कुछ करना चाहिए। ब्रेनित्जकी की इस धमकी के बाद एक टीवी प्रसारण में डा० वाल्डहाइम ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह विवाद उनके खिलाफ यहूदियों की साजिश का एक अंग है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ देश उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।

किस्सा चाहे कुछ भी हो, सारे प्रसंग पर गौर करने के बाद पश्चिम की एक हास्यास्पद तस्वीर ही सामने आती है। गड़े मुरदे उखाड़कर कोरी नैतिकता की दुहाई देना मजाक नहीं तो और क्या है? वही पश्चिम जो दुनिया को उदार सेक्स के विचार बांटता-फिरता है, सीनेटर गैरी हार्ट की राष्ट्रपति-पद से उम्मीदवारी को सिर्फ इस बिना पर खारिज कर देता है कि माडल गर्ल डोना राइस से कभी उनके सेक्स संबंध थे। अमरीका एक विद्वान को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इसलिए नहीं बनाता कि बचपन में उसने एक बार मारिजुआना (मादक द्रव्य) पिया था। कुर्ट वाल्डहाइम ने ४५ साल पहले क्या किया था, यह उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आज वह क्या हैं। वह दस साल तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे और अब आस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं। क्या ये बातें उनकी योग्यता को प्रमाणित करने के लिए काफी नहीं हैं?

EP/LIC-90/88 HIN

बांगलादेश

इरशाद की जिद

स्थानीय चुनाव में हुई भयानक हिंसा ने राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद की गद्दी और आगामी चुनाव के सामने कई प्रश्न चिह्न खड़े कर दिये हैं। मसलन, क्या राष्ट्रपति इरशाद अपनी गद्दी बचाये रख सकेंगे? क्या विपक्ष के इतने विरोध के बावजूद चुनाव करवा पायेंगे? या फिर जब स्थानीय चुनाव में ही १०० से ज्यादा लोगों ने जानें गवां दीं, तो आम चुनाव में क्या हाल होगा?

१९७१ में स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश में यह चौथे पंचायत चुनाव थे। स्थानीय परिषदों के लगभग ४४००० सदस्यों और मेयरों का चुनांव होना था। लेकिन लगभग तीन महीने पहले विपक्षी दलों द्वारा शुरू किया गया 'इरशाद हटाओ' आंदोलन थमा नहीं था और हड़तालों तथा बंदों का सिलसिला जारी रहा। २७ नवंबर को राष्ट्रपति इरशाद ने इमर्जेंसी लागू करने के बाद चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी, मगर प्रमुख विपक्षी दलों ने यह कहकर चुनावों को बहिष्कार करने की घोषणा कर दी कि इरशाद के सत्ता में रहते निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना नहीं है। इस सबके बावजूद इरशाद अपने फैसले पर अटल रहे और इसी धुन में पंचायत चुनाव भी उन्होंने आयोजित करवा डाले।

विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल होने के समय हड़तालों का आयोजन किया था। उसी समय यह साफ हो गया था कि उनका मंशा केवल चुनाव का बहिष्कार करने भर का नहीं, बल्कि चुनाव न होने देने का भी है। इसीलिए मतदान के समय भारी सुरक्षा-बंदोबस्त के बावजूद इरशाद की जातीय पार्टी और विपक्षी दलों के समर्थकों के बीच आपस में ठन गयी। बंदूकों, चाकुओं और देशी बमों का खुलकर प्रयोग हुआ जिससे १०० के करीब लोगों की मृत्यु हो गयी और २००० के आसपास घायल हो गये। प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया ने तो यहां तक कहा है कि ५०० से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और ५००० से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।

पंचायत चुनाव में हुआ रक्तपात राष्ट्रपति इरशाद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन अभी भी उन्होंने चुनाव कराने की जिद छोड़ी नहीं है। उनकी यह जिद बांग्लादेश को किस ओर ले जायेगी, कहना मुश्किल है। दरअसल इरशाद के लिए चुनाव करवाने का सवाल उनके अस्तित्व से जुड़ गया है। यह भी तय है कि विपक्षी दल लोकतंत्र-बहाली और इरशाद हटाओ का अपना अभियान किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। इस सबका सीधा सा मतलब है—टकराव। इरशाद ३ मार्च को होने वाले आम चुनाव में कितना ही फौजी पहरा बिठा दें, हिंसा को रोक पाना मुश्किल होगा।

अपने नये अभियान के तहत इरशाद की पुलिस ने कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया है और फौज की सहायता लेने की घोषणा भी कर दी है। संभव है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। उनका खयाल है कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से आंदोलन थम जायेगा और वह शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित करवा लेंगे, लेकिन ऐसा सोचना मुसीबत को न्यौता देना ही कहा जायेगा। यह प्रयोग वह एक बार पहले भी कर चुके हैं और उस बार की तरह आंदोलन के जोर पकडने और हिंसा भड़कने की ज्यादा गुंजाइश है।

एक सवाल यह भी है कि यदि किसी तरह वह चुनाव करवाकर जीत भी गये, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जनता चुनाव परिणाम को स्वीकार कर ही लेगी। १९८२ में रक्तहीन सैनिक तख्तापलट के जरिये सत्ता में आने वाले इरशाद ने १९८६ में ऐसे ही चुनाव आयोजित करके खुद की स्थिति संवैधानिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन डेढ साल बीतते-न-बीतते फिर चुनाव कराने की नौबत आ गयी। जाहिर है, बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का हल ये चुनाव हरगिज न बन पायेंगे।

फिलिस्तीनियों का जेहाद

इस मर्ज का इलाज दमन नहीं, आजादी है

गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीनियों द्वारा इस्राइल विरोधी प्रदर्शन को तीन महीने से ज्यादा हो रहे हैं, मगर समस्या के सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस्रायली फौजों द्वारा फिलिस्तीनियों का दमन जारी है। अभी तक लगभग ६५ लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या भी हजारों में है। प्रदर्शन, आंदोलन और बंद अभी भी जारी हैं और यदा-कदा हिंसा भी भड़क उठती है। इस्रायली सरकार यह दावा भले ही करती हो कि उसकी फौज अब सख्ती नहीं दिखा रही, मगर वहां से आ रही सूचनाएं उसके दावों की धज्जियां उड़ा देती हैं। हाल में उसकी फौज ने एक गांव में चार फिलिस्तीनियों को गर्दन तक जमीन में गाड़कर बुल्डोजर चढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु गांववालों के हस्तक्षेप से उन्हें सफलता नहीं मिली।

यों तो समस्या को निपटाने के प्रयास जोर-शोर से किये जा रहे हैं, मगर नजदीक में किसी समाधान की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। मिश्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने हाल में अमरीका और फ्रांस की यात्रा की थी। इसी तरह जार्डन के शाह ने भी अरब देशों की यात्रा की है।

दरअसल इस समस्या की चाभी केवल इस्रायल और अमरीका के पास है और जब तक वे नहीं चाहेंगे सभी प्रयास बेकार जायेंगे। इन दोनों का इरादा फिलहाल मामले को टालने का है। इस्रायल तो किसी भी हालत में अपना कब्जा हटाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। जहां तक अमरीका का सवाल है, ऐसे कई कारण हैं जो उसके इरादों को संदिग्ध बताते हैं। हाल में उसने दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र में इस्रायली करतूतों की निंदा वाले प्रस्ताव को वीटो किया था। मानवीय अधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाले अमरीका ने इस प्रस्ताव को वीटो करके जाहिर कर दिया कि इस्रायली सैनिकों द्वारा मानवीय अधिकारों के हनन को वह समर्थन और सहयोग दे रहा है। इसी तरह उसने पी०एल०ओ० (फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन) के न्यूयार्क स्थित कार्यालय को बंद करने की भी घोषणा की है।

शांति के लिए अमरीका जो प्रस्ताव पेश कर रहा है, वह भी उसके टालू रवैये का परिचायक है। अपने प्रस्ताव में अमरीका ने सुझाया है कि इसी साल सितंबर तक इस्रायल अधिकृत क्षेत्र को सीमित स्वायत्तता दे दी जाये और फिर उसके बाद साल भर के अंदर उसका हाल खोजने की कोशिश की जाये। यह समझौता १९७८ में इस्रायल और मिश्र के बीच हुए 'कैंप-डेविड समझौते' का ही एक रूप है और इस समझौते की तभी से जमकर आलोचना होती आ रही है। इस प्रस्ताव से अमरीका एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहले तो सीमित स्वायत्तता देकर जारी विरोध को फिलहाल शांत किया जाये और फिर बाद में अपने मन मुताबिक कोई समझौता करवाकर मामला निपटा लिया जाये। इस प्रस्ताव से दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों का स्वार्थ भी जुड़ा है। दोनों ही देशों में इसी साल चुनाव होने हैं और कोई नहीं चाहता कि फिलिस्तीनियों को आजादी देकर चुनाव हार जाये। यद्यपि राष्ट्रपति रीगन चुनाव नहीं लड़ रहे, मगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी का भाग्य तो दांव पर लग ही जायेगा।

उधर सोवियत संघ ने भी एक प्रस्ताव सामने रखा है। प्रस्ताव में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत बतायी गयी है। सभी अरब राष्ट्र उसके इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, मगर इस्रायल को यह प्रस्ताव फूटी आंख नहीं भा रहा। वह जानता है कि विश्व जनमत उसके खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मांग को मान लेने का सीधा सा मतलब है—फिलिस्तीनियों की आजादी।

फिलिस्तीनियों की हिम्मत को दाद दिये बिना भी नहीं रहा जाता। छोटे-छोटे बच्चे, क्या लड़के और लड़कियां सभी हथियारबंद इस्रायली सैनिकों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ने में भी नहीं हिचक रहे हैं। पी०एल०ओ० ने भी अपनी छापामार कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं। पिछले दिनों एक युवक ने ग्लाइडर की सहायता से एक इस्रायली फौजी कैंप पर हमला करके चार सैनिकों को मार डाला और फिर खुद को गोली मार ली।

—मुकेश

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय —१०५ रोहित हाउस,

राधा पॉकेट बुक्स

के नये सैट में पढ़िए

DUPLICATE

सुपर स्टार
उपन्यासकार

परशुराम शर्मा

का नया उपन्यास

जुर्म का देवता

10/-

परशुराम शर्मा
जुर्म का देवता
नया उपन्यास
जुर्म का देवता
परशुराम शर्मा

परशुराम शर्मा का 1988 में लिखा गया
प्रथम धड़कता थ्रिलर उपन्यास
ड्रग्स तस्करों की दुनिया में
हाहाकारी जंग का ऐलान

युवा उपन्यासकार

वेद प्रकाश शर्मा

का महान उपन्यास

नसीब मेरा दुश्मन

10/-

वेद प्रकाश शर्मा
नसीब मेरा दुश्मन
नसीब मेरा दुश्मन

राधा पॉकेट बुक्स
33, हरी नगर, मेरठ 250002

ये मुस्कान रहेगी कायम

जिस दिन से मिल गया उसे अनचाहे गर्भ से छुटकारा,
उसकी खुशियों का झिलमिलाया सितारा।
अपने परिवार को छोटा रखने के लिए आज
संसार में साढ़े छः करोड़ से भी ज्यादा औरतें ओरल पिल्स यानि
गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हैं।
उन्हीं की तरह उसने भी माला-डी-नई छोटी
खुराक वाली गोलियां खाना शुरू कर दी हैं।
ये गोलियां खासतौर से भारतीय महिलाओं
के लिए अनुकूल हैं।
पहला बच्चा जल्दी नहीं,
दूसरा उसके तीन साल बाद
और इसके लिए हर समझदार औरत खाती है गर्भ निरोधक
गोलियां
माला-डी-गोलियों के प्रयोग से छाती का कैंसर,
डिम्ब ग्रंथि का कैंसर, गर्भाशय कैंसर तथा पेडू
में सूजन जैसे रोग का खतरा कम हो जाता है।

**डाक्टर की सलाह लीजिए,
वह आपको माला-डी की राय देंगे।**

Rx
माला·डी
Mala·D
निरोधक गोलियां
CONTRACEPTIVE PILLS
स्त्रियों के लिए खाने की गोली
for oral use by women

**माला-डी, बच्चों के जन्म में अन्तर के लिए
सुरक्षित, सरल और शर्तिया उपाय
नई खाने की गर्भ-निरोधक गोलियां,
रियायती दामों पर,
सिर्फ 2 रु. में एक पैकेट।**

डी ए वी पी 87/146

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

१५ अप्रैल, १९८८

माया

वर्ष ५९ अंक ७

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र

प्रधान संपादक
आलोक मित्र

संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा

उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू

ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार

वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़

विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा

संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी

कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी

सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५६६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

यह अंक

आवरण कथा

माया
ज्ञानीजी का दोहरा खेल
साजिश राजीव के खिलाफ या मंत्रियों के ?
क्या वेंकटरमण प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार थे ?

३०

ज्ञानी जैल सिंह द्वारा यह धमाका करने के बाद कि उनको दुबारा चुनाव लड़ने के लिए ३०-४० करोड़ रुपए देने की पेशकश की गयी थी, सत्तापक्ष और विपक्ष में सनसनी फैल गयी है। लेकिन ज्ञानीजी ने इस संदर्भ में जो दुबारा रहस्योद्घाटन किया है, उससे राजीव गांधी के सामने अजीब संकट पैदा हो गया है। क्या वेंकटरमण प्रधानमंत्री बनने की ताक में बैठे थे ? क्या ज्ञानीजी राजीव गांधी के इशारे पर चल रहे हैं या अपने आप यह धमाका कर रहे हैं ?

विशेष रिपोर्ट
लोकदल-अ और संजय मंच के जनता पार्टी में विलय से जपा की ताकत बढ़ी या घटी ? २०

अर्जुन सिंह
अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने पुत्र के लिए सत्ता का रास्ता निष्कंटक बनाने के लिए अर्जुन सिंह किस तिकड़म में लगे हैं ? ५६

दिनेश सिंह
काफी लंबे वनवास के बाद सत्ता में लौटे दिनेश सिंह से 'माया' की खास बातचीत : १४

भगत
हरकिशन लाल भगत को दिल्ली की राजनीति का बेताज बादशाह क्यों माना जाता है ? ६२

मेनका
संजय मंच के जनता पार्टी में विलय के बाद मेनका का भविष्य क्या है ? २६

कर्ण सिंह
देश की सबसे बड़ी पांच भूतपूर्व रियासतों में एक जम्मू-कश्मीर के वंशज डा० कर्ण सिंह की राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा का जायजा ८४

दिल्ली दरबार :...तो आइडिया यों सूझा... ६
उम्मीद : शुजुद्दीन साजिद : रिश्वतखोरो सावधान १९
प्रसंगवश : कानून का पालन करें या आकाओं के हुक्म की तामील ४२
पश्चिम बंगाल : पंचायत चुनाव : वाममोर्चे में दरार ४५
महाराष्ट्र : आदिवासी : शोषण चालू आहे ४८
बिहार : सोन नदी : किसानों के प्रति सरकार की हमदर्दी का नमूना ५३
मध्य प्रदेश : बीटीवीटीसी : विकलांगों पर नौकरशाही का नजला ५८
राजस्थान : माथुर के राज में औरत ६०
उत्तर प्रदेश : अफसर बनाम विधायक ६६
उत्तर प्रदेश : अक्षयवरमल की हत्या ? ६८
खेल : क्या गुल खिलायेगी शाहिद की वापसी ? ६९
अर्थतंत्र : कर्ज का कसता फंदा ७०
पुस्तक चर्चा : '४० साल' पर विवाद क्यों ? ७२
फिल्म : वक्त के साथ बदलने का नाम है शशिकपूर ७६
अभिमत : प्रोफेसर ए० रहमान : दोहरे चरित्र का संकट ८०
धन-धंधा ८२
विदेश ८८
दूरदर्शन : चूं-चूं का मुरब्बा १००
परदे के पीछे १०२

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आवरण पारदर्शी : एन० प्रसाद

किस लिए ?

'माया' के १५ मार्च '८८ की आवरण कथा 'राज्यों और केंद्र में फेरबदल किस लिए ?' अच्छी लगी। इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर वीपी सिंह का भूत सवार है और यही कारण है कि अगले चुनाव का खयाल रखते हुए केंद्र और राज्यों में परिवर्तन किये गये हैं। राजीव गांधी अगले चुनाव के लिए जो भी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, उससे देश के सच्चे तथा समझदार देश भक्त वाकिफ हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कुछ भी करने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं। केंद्र सरकार जानती है कि देश की अधिकांश जनता इतनी भोली-भाली है कि उसे जाति और धर्म के नाम पर फुसलाया जा सकता है। यदा-कदा हमारी सरकार जातिवाद की बुराइयों के खिलाफ लंबी-चौड़ी बातें करती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वह स्वयं इसे प्रोत्साहित करती है, जैसा कि केंद्र तथा राज्यों के फेरबदल में अभी-अभी किया गया है।

अंग्रेजी सरकार की हम आलोचना करते थे कि उसने 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनायी थी और इसी नीति के सहारे सैकड़ों वर्षों तक वह हम पर शासन करती रही। लेकिन आजादी के चालीस वर्षों के बाद भी हम इस नीति के शिकार हैं। अगर हमारी वर्तमान भ्रष्ट सरकार इसी नीति के सहारे एक लंबे अरसे तक हम पर शासन करती रही, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?**—परम हंस सिंह, आरा, बिहार**

'राज्य व केंद्र में परिवर्तन किस लिए ?' (मार्च प्रथम) पढ़ा। आजादी के बाद से केंद्र व अधिकांश राज्यों में लगातार सत्तारूढ़ रहनेवाली कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि वहा का नेतृत्व कभी भी सर्वसम्मत नहीं रहा। संगठन में जहा गुट सक्रिय रहे हैं, वहीं विधायकों की निष्ठा कुछ व्यक्तियों में रही जो परिवर्तनशील रही। निष्ठा के परिवर्तन के कोण भी अलग-अलग रहे हैं, कभी पद, तो कभी पैसा। इन परिस्थितियों में केंद्र से नेतृत्व थोपने की एक गलत परंपरा पड़ गयी, यह थोपा गया नेतृत्व कभी कांग्रेसी विधायकों द्वारा एकमत से ईमानदारी से नहीं स्वीकारा गया। नेतृत्व-परिवर्तन के साथ ही दूसरा ग्रुप सक्रिय हो उठा और असंतुष्टों के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सका। नेतृत्व में परिवर्तन के साथ ही मुख्यमंत्रियों ने अपने कथित वफादारों को कुरसी सौंपकर कृतार्थ कर दिया। पर इन सारे उपक्रमों के उपरांत भी वेगमयी अस्थिरता की अंतर्धाराओं के प्रवाह से विचलित रहा नेतृत्व। अवसर की रबड़ी हाथ लगते ही इन नेताओं ने अपनी जेबें भरीं। लोकतंत्र के भाग्यनिर्धारक मतदाताओं से निर्वाचित सरकार के संचालन के लिए नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा थोपा गया। अत: यह कहा जा सकता है कि राज्य व केंद्र में बार-बार परिवर्तन के लिए कांग्रेस की अंतर्कलह जिम्मेदार रही।**—ज्ञानेश चौबे, १७/५० आजादगंज हरदा, मध्य प्रदेश**

'आवरण कथा' कांग्रेस-इ के राजनीतिक समीकरण और उठापटक की सारी तस्वीर साफ करती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सारी उठापटक राजीव गांधी की उद्विग्नता (जो कि चुनाव के भविष्य को देखते हुए उपजी है) की रामकहानी कहती है। उन्हें यह अहसास हो गया है कि अगले चुनाव को जीतने के लिए 'साम, दाम, दंड और भेद' नीति पर चलकर सफलता पायी जा सकती है।**—प्रकाश पालीवाल, अकलतरा, मध्य प्रदेश**

जिस प्रकार एक साथ तीन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल हुआ, वह अप्रत्याशित नहीं था। कांग्रेस-इ पार्टी में अंदर-ही-अंदर गुटबाजी पनपती जा रही थी जो धीरे-धीरे नासूर का रूप ले रही थी।

राजस्थान में हरिदेव जोशी का हटना खतरे से खाली नहीं है। अगर हरिदेव जोशी खुलकर बगावत पर उतर आये, तो वहां माथुर सरकार का गिरना असंभव नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश में बजट सत्र के चलते नेतृत्व परिवर्तन करना हास्यास्पद लगता है। प्रधानमंत्री ने यह कदम हड़बड़ाहट में उठाया है। अर्जुन सिंह के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि कांग्रेस अपार बहुमत पा जायेगी। अभी तो उनको खुद का चुनाव जीतना बहुत भारी पड़ेगा। ये वही अर्जुन सिंह हैं जिन पर सैकड़ों भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के आरोप हैं और पुन: उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तित्व के सामने प्रश्न चिह्न लगा दिया है ? उनकी 'मि० क्लीन' की छवि बुरी तरह धूमिल हो गयी है।**—डा० दीनदयाल 'बसंत', वृंदावन, उत्तर प्रदेश**

प्रधानमंत्री फेयरफैक्स जैसे कांडों से जनता का ध्यान बंटाने के लिए कभी अपना उत्सव कभी भारत उत्सव तो कभी दौड़ों का आयोजन करते हैं। अगर मध्यावधि चुनाव की तैयारी के उद्देश्य से फेरबदल किया है, तो वह भी गलत है। अभी तो प्रधानमंत्री फेयरफैक्स जैसे कांडों का ठीक जवाब तक नहीं दे पाये हैं। अगर वह यह चुनाव कारायेंगे, तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।**—भरत जैन, १७/१३६, शास्त्री वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश**

राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या

१५ मार्च '८८ की 'माया' पढ़ी। श्री भीष्म साहनी के लिखे लेख 'राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या' पढ़कर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर उर्दू के साथ अन्याय और सौतेला बर्ताव कब तक होता रहेगा ? आखिर वह दिन कब आयेगा जब हिंदी के साथ उर्दू भी इस देश और इस मिट्टी की जुबान समझी जायेगी। उर्दू किसी एक मजहब, किसी एक जाति की भाषा नहीं, वरन यह सबकी भाषा है। आखिर हमारे रहनुमा कब तक भाषा की लड़ाई छेड़कर अपनी सियासत को कामयाब बनाते रहेंगे।

किसी देश की तरक्की में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब भी वक्त है। यदि समय रहते हम इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी प्रगति की राह बड़ी कठिन होगी।**—मु० शहाबुद्दीन खां, बहेरी, बलिया, उत्तर प्रदेश**

भीष्म साहनीजी के युक्तिपूर्वक लिखे गये लेख से यह तो स्पष्ट ही है कि माननीय लेखक उर्दू की हिमायत कर रहे हैं, किंतु कतई बुरा नहीं लगा। भाषा को विशेष वर्ग से जोड़ना हालांकि उचित नहीं है, क्योंकि भाषा तो भाव व्यक्त करने का माध्यम मात्र है। किंतु साहनी साहब उर्दू की जबरदस्त वकालत करते-करते संस्कृत को आक्रमणकारियों की भाषा कह गये। यह तो ऐसा ही हुआ कि एक मजा वकील अपने तथ्य को सत्यता का जामा पहनाने के लिए असत्य की शाही-बैसाखियों का सहारा ले। **—राकेश त्रिपाठी, २२ अ/१, विजय नगर, कानपुर**

'तमस' के द्वारा मुसलमानों को हिंदुओं के जुल्मोसितम का शिकार प्रचारित कर साहनी साहब का ध्यान अब इस देश में उर्दू के साथ हो रहे अन्याय की ओर गया। बड़े आश्चर्य एवं निर्लज्जता की बात तो यह है कि वह उर्दू को आक्रमणकारियों की जबान स्वीकारते समय 'संस्कृत' को भी आक्रमणकारियों की जबान कह कर गाली देने से नहीं चूकते हैं। यदि संस्कृत विदेशी आक्रमणकारियों की भाषा है, तो साहनी साहब संस्कृत में एक भी ऐसी रचना दिखाएं जिसमें किसी बाह्य देश को भारत से श्रेष्ठ और पुण्य भूमि माना गया हो, जिस प्रकार उर्दू में विदेशों का गुणगान कर उसे पुण्य भूमि मानकर भारत से श्रेष्ठ बताने वाली सहस्त्रों की संख्या में रचनाएं उपलब्ध हैं और रची जा रही हैं।

क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि भारत का बंटवारा अहिंदी-सामान्यतया उर्दू भाषी क्षेत्र में ही हुआ है, उसकी मांग भी उर्दू भाषा में ही की गयी। इतिहास साक्षी है कि हिंदुस्तान का वही हिस्सा कमजोर हुआ अथवा टूटा जहां हिंदी कमजोर थी।

यह ठीक है कि उर्दू भारत में ही जनमी, परंतु उर्दू भाषा और साहित्य हिंदू-मुस्लिम संस्कृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम नहीं है। स्पष्टतया यह इस्लामी स्वर का भारतीय संस्करणमात्र है। यही कारण है कि उर्दू भाषा अब तक इस्लामी दायरे को लांघ नहीं पायी है।**—जयदेव शर्मा, ८४, सदर बाजार, लखनऊ**

उनका कहना सही है

१५ मार्च. १९८८ के अंक में पंजाब के राज्यपाल श्री रे का साक्षात्कार पढ़ा। उनका कहना सचमुच सही है कि निन्यानबे प्रतिशत लोग खालिस्तान विरोधी हैं। भारतीय इतिहास में कट्टरता तथा सहिष्णुता के प्रभाव को भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह एक ओर विशेषाधिकार प्राप्त शक्तिशाली लोगों तथा दूसरी ओर मानवतावादी विचारों से प्रभावित आम जनता के बीच के संघर्ष का एक रूप है।

हम देखते हैं कि कट्टर विचारकों तथा प्रचारकों का प्रभाव बड़ा सीमित होता है और इनसे बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों की यही आशा रहती है कि उन्हें धनी समाज और राज्य में प्रतिष्ठित लोगों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरी ओर सहिष्णुता के समर्थक विचारकों से आम जनता प्रभावित होती है। कट्टर तथा संकीर्ण तत्वों के प्रभाव तथा उनके द्वारा प्रतिपादित संकीर्ण विचारों से हमारे देश की सांस्कृतिक एकता में बाधा पहुंचती है। आज अगर कट्टर तथा संकीर्ण विचारों की ओर साधारण जनमानस झुकने भी लगा है, तो उसके लिए लोकतंत्र के ऐयाश पुत्र ही दोषी हैं।—**राजीव लोचन मंटू, घोसैठ, पीरी बाजार, मुंगेर, बिहार**

अधर में

१५ मार्च '८८ की 'माया' में 'भाग्य निर्माताओं का भाग्य अधर में' पढ़ा। चुरहट लाटरी कांड के बारे में अब प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और विवाद एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आसवानी कांड में तो उन्होंने हाई कोर्ट के निर्णय की सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़वा दी थीं। जो भी काम अर्जुन सिंह करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार ही क्यों न हो। आज जबकि चुरहट लाटरी कांड अदालत में है, उसका भी हश्र आसवानी कांड जैसा ही होगा। जब प्रधानमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो समझिए सारे विवाद समाप्त, क्योंकि प्रधानमंत्री 'मि० क्लीन' हैं, अतः अर्जुन सिंह भी आटोमेटिक 'मि० क्लीन' हो गये। वैसे सीधी के वर्तमान जिलाधिकारी श्री राकेश अग्रवाल चाहें, तो चुरहट लाटरी से संबंधित तमाम सही तथ्य उजागर कर सकते हैं, क्योंकि श्री अग्रवाल निर्भीक हैं। वैसे भी चुरहट लाटरी से संबंधित विवाद शांत होने में देर न लगेगी, क्योंकि अर्जुन सिंह न्यायपालिका को भी कब्जा में रखने का मंत्र जानते हैं। —**अजय राज द्विवेदी, शहडोल, मध्य प्रदेश**

व्यक्ति को सजा या प्रतिभा को?

'माया' (१५ मार्च) में 'व्यक्ति को सज़ा या प्रतिभा को?' छपा आलेख अक्षरशः सत्य है। निःसंदेह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बचकाना व्यवहार को दिलीप वेंगसरकर की खेल प्रतिभा पर प्राणघातक हमला माना जायेगा। वैसे भी अपने इस निर्णय से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा लिये हुये हैरतअंगेज निर्णयों को भी एक कदम पीछे छोड़ दिया है।

मुझे सभी विवेकशील क्रिकेट प्रेमियों की ओर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड से नम्र निवेदन करना है कि वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी नियम-परिपाटी में खिलाड़ियों से समझौते का पक्ष प्रबल रखे जिससे कोई भी खिलाड़ी बोर्ड की नीतियों पर भली-भांति अमल कर सके। क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस मामले को खिलाड़ी की सेवाओं को देखकर रद्द नहीं कर सकता?—**सुनील कुमार, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश**

अच्छा नहीं किया

'माया (२९ फरवरी '८८) में 'टिकैत द्वारा मेरठ कमिश्नरी का घेराव' में मुझे लगा कि टिकैत अपना आंदोलन चलाने में सरकार के सामने कामयाब नहीं हो सके। अंततः कांग्रेस सरकार के कहने पर उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले ही लिया। इससे किसान ही नहीं समूचे नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो किसानों ने अपनी मांगों के लिए बलिदान तक कर दिया और दूसरी तरफ टिकैत ने नाम कमा कर सरकार के कहने पर आंदोलन वापस ले लिया। टिकैत को ऐसा नहीं चाहिए था। यदि वह अपना धरना निश्चित समय तक कायम रखते, तो सफलता उनके हाथ अवश्य लगती।

—**महेंद्र कुमार तिवारी, रीवा, मध्य प्रदेश**

खयालात

'शहंशाह जीतेगा।'—**गुलाम नबी आजाद से यह पूछने पर कि इलाहाबाद उपचुनाव कौन जीतेगा?**

डा० राजेंद्र प्रसाद और डा० राधाकृष्णन सरीखे राष्ट्रपतियों की पंक्ति में तो वह (ज्ञानी जैल सिंह) कहीं भी नहीं ठहरते, पर चर्चा में बने रहने की रणनीति तैयार करने और उसे अख्तियार करने में वह माहिर हैं।—**'रांची एक्सप्रेस' की संपादकीय टिप्पणी से**

राजीव गांधी में अपनी मां जैसी जुआ खेल कर जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है।—**जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर समरगुहा की मध्यावधि चुनाव के बारे में राजीव के रुख पर टिप्पणी**

सरकार की शवयात्रा शुरू हो गयी है, भले ही अंतिम संस्कार दो साल बाद हो।—**विश्वनाथ प्रताप सिंह, 'जनसत्ता' में**

मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि लक्षद्वीप की यात्रा मैंने व्यक्तिगत खर्चे पर की है।—**राजीव गांधी, 'नवभारत टाइम्स' में**

भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की पहल पहले भारत को ही करनी होगी। —**पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक**

निस्संदेह श्रीमती इंदिरा गांधी के किसी निर्णय से इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी क्षति ज्ञानी जैल सिंह को पहले केंद्रीय गृहमंत्री और फिर देश के राष्ट्रपति बनाने से हुई। इस भूल की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।—**निखिल चक्रवर्ती, 'मेनस्ट्रीम' में**

किरण बेदी ने वकीलों के साथ बलात्कार किया है। यह अलग बात है कि वह बलात्कार करने में असमर्थ हैं।—**उच्चतम न्यायालय के वकील गोविंद मुखौटी, इंडियन एक्सप्रेस में**

भारत को १९९७ तक आर्थिक संकट और मंदी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद स्वर्णयुग आयेगा और उसकी गिनती जापान-अमरीका जैसी आर्थिक शक्तियों में होगी।—**मशहूर अर्थशास्त्री और लेखक डा० राजीव बत्रा**

किसानों के हमदर्द राजीव बिलकुल नहीं हैं। हमदर्द होते, तो राजस्थान नहर कभी की बन गयी होती।—**देवीलाल, 'धर्मयुग' में**

अमरीका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा।—**जार्ज बुश**

दूरदर्शन एक धर्मनिरपेक्ष कठपुतली है जो सांप्रदायिक तत्वों के नियंत्रण में है।—**डा० राही मासूम रजा 'हिंदुस्तान टाइम्स' में**

अमिताभ बच्चन को राजनीति और रेखा—दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें दोनों त्याग देना चाहिए।—**शत्रुघ्न सिन्हा 'टेलीग्राफ' में**

वास्तविक जीवन में भी लोग चाहते हैं कि मैं सीता जैसा ही व्यवहार करूं।—**'रामायण' सीरियल की सीता—दीपिका, 'माधुरी' में**

जिया-उल-हक

देवीलाल

दीपिका

...तो आइडिया यों सूझा...

दिल्ली दरबार आजादी की 'मैराथन दौड़' में मुल्क के हर लूले-लंगड़े को दौड़ा कर अपने ढाईलखा शाही पलंग (बकौल राजा मांडा) पर मय ट्रैक सूट के जा गिरे। वह कम्बल ओढ़ कर खर्राटे भरें कि उसके पहले विज्ञापनी मदारी रोमी चोपड़ा अपनी दाढ़ी खुजलाते शाही पलंग के पैताने आ खड़े हुए। रोमी के कंधे पर, दोनों हाथों से अपनी दाढ़ी की खुजलाहट मिटाते हुए सुरेश कलमादी चढ़े हुए थे। रोमी कोई मल्टीनेशनल विज्ञापनी दांव मारें कि उसके पहले कलमादी फुदक कर नीचे आ टपके और 'जबानी जमा खर्च' की मैराथन दौड़ शुरू कर दी, "सर, आपके इस आइडिए ने सारे मुल्क को नचा दिया है। मुल्क की जड़ता टूट गयी है। पूरा मुल्क आगे को मुंह बाये बस दौड़े ही जा रहा है। मुल्क को २१ वीं शताब्दी में खदेड़ कर पहुंचा देने का 'यह नून लगे न फिटकरी' वाला जो नायाब आइडिया इस पलंग पर सोने वाले आपके पुरखों को नहीं आया, वह आपको आ गया। अब सारा मुल्क झख मार कर २० वीं शताब्दी की दीवार फांद कर अपने आप २१ वीं शताब्दी में औंधे मुंह जा गिरेगा। हुजूर, अब आप २१ वीं शताब्दी के बचे हुए सालों में कंबल में मुंह ढंक कर सोयें।" रोमी की जेब में पड़े विज्ञापन-बिल जब खड़खड़ाये, तो उन्होंने लम्बे कद का तुरन्त फायदा उठाया। सुरेश कलमादी को ढंक कर उनके जबानी जमा खर्च की मैराथन को बीच में लंगड़ी मार दी. "सर, हेलीकाप्टर से हिचवायी-खिंचवायी है यह पूरी फिल्म। राजपथ से जनपथ तक आदमी ही आदमी। हुजूर, बेतहाशा दौड़ता हुआ आदमी तिरंगे में बदल जाता है। पैसा तो थोड़ा ज्यादा जरूर लग गया है, लेकिन संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दीजिए। सर, आने वाली पीढ़ी यही समझेगी कि...।" दिल्ली दरबार रोमी की विज्ञापनी बातें सुनकर शाही पलंग पर उछल पड़े—"अरे रोमी, देर क्यों कर रहे हो। फौरन फिल्म को वीडियो पर चढ़ाओ...।" रोमी ने लपक कर अपने झोले से कैसेट निकाला, तो आगे बढ़कर गुलाम नबी आजाद ने आस्कर फर्नांडीस और पनिक्कर की मदद से उसको रोक लिया, "रोमी तेरे बिल पास हो गये। चैक दफ्तर से ले लें।" रोमी फौरन से पेश्तर चैक लेने के लिए उड़नछू हो लिये। दिल्ली दरबार आपे से बाहर हों कि उसके पहले गुलाम ने फरशी सलाम ठोंक कर स्थिति को संभाल लिया, "हुजूर विरोधी दलों में एकता हो रही है।" दिल्ली दरबार बिगड़ उठे, "एकता की महान दौड़ हम लोग करायें और एकता विरोधी दलों में हो, यह क्या मजाक है?" दरबार के चढ़े तेवर को 'नार्मल' करने के लिए आस्कर फर्नांडीस ने फौरन कर्नाटकी गायन में आलाप लेना शुरू कर दिया, "सर, हम लोगों ने अपने दलालों को उकसा दिया है। वे लोग तोड़फोड़ करने के लिए जुट गये हैं। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से लोकदल का 'ए' 'बी' से अलग कराया था। लेकिन वह 'ए' जनता पार्टी की दाढ़ी में चिपक गया।" दिल्ली दरबार ने बीच में ही टोका—"वह 'ए' (अजीत सिंह) तो कंप्यूटरी था, फिर जनता पार्टी की दाढ़ी में उसे चिपकने की क्या जरूरत पड़ गयी? हम तो सोच रहे थे कि उसे अपने दरबार में ले लेंगे," पनिक्कर ने आगे बढ़कर बोलना शुरू किया। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने पनिक्कर को पीछे धकिया दिया, "हुजूर 'ए' पर हम लोगों ने काफी रियाज मारा। वह आने के लिए मूड बना ही रहा था, लेकिन जनता पार्टी की दाढ़ी बराबर बीच में भांजी मारती रही।" इसी बीच दिल्ली दरबार आस्कर की तरफ मुखातिब हो लिये, "अरे आस्कर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कर्नाटकी दाढ़ी वाला (रामकृष्ण हेगड़े) बलियाटिक दाढ़ी पर चढ़ा हुआ है। क्या तुम्हारे कर्नाटकी दाढ़ी वाले ने घुटने टेक दिये?" आस्कर की सिट्टी-पिट्टी बंद हुई, तो गुलाम नबी और पनिक्कर भी पीछे हो लिये, ताकि दिल्ली दरबार को आस्कर पर चढ़ बैठने में आसानी हो। आस्कर ने जेब से रूमाल निकालकर पहले अपने जबड़े को खींचकर खोला फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया, "सर, वह अपना कर्नाटकी दाढ़ी वाला लगा तो हुआ है, उस बलियाटिक दाढ़ी वाले के पीछे, लेकिन..." इतने में मौका पाकर पनिक्कर आगे की ओर धंस लिये, "सर जब मैंने देखा कि आस्कर कर्नाटकी दाढ़ी वाले को उकसा पाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपने उड़ियावाले बीजू (पटनायक) को अपने आदमियों से पानी पर चढ़वा दिया। वह आपे से बाहर होकर बलियाटिक दाढ़ी को नोचने पर उतारू है।" आस्कर ने मौका पाकर नहले पर दहला मारा, "सर, जब वह कर्नाटकी दाढ़ी कब्जे में नहीं आयी, तो जात-बिरादरी की दुहाई देकर मैंने अपने जार्ज फर्नांडीस को उस बलियाटिक दाढ़ी पर दाना-पानी लेकर चढ़वा दिया है। वह दाढ़ी की ऐसी, ऐसी-तैसी करेगा कि लोकदलीय 'ए' को सीधा 'परलोक' नजर आयेगा। आप सर, कंबल ओढ़कर सोयें। हम लोग आपकी नींद में कतई खलल नहीं पड़ने देंगे।" आस्कर अपना वाक्य पूरा कर ही पाये थे कि गुलाम नबी ने मधु दंडवते को लेकर अपनी बात शुरू की कि पुराने खबरची सुमन दुबे एक बगल में एक कैसट तथा दूसरी बगल में मणि शंकर अय्यर को दबाये आ धमके। आगे कोई और कुछ बोले कि सुमन दुबे ने बिजली गुल कर दी, "सर स्क्रीन पर देखें। यह बलियाटिक दाढ़ीवाले का गुडगांव के करीब भौंड़सी में भारत यात्रा आश्रम है। वह देखिए इमरजेंसी नरेश (स्व०) ओम मेहता की लड़की से अपने बेटे का गुपचुप विवाह रचाकर बहुत गुमसुम बलियाटिक दाढ़ी वाला भौंड़सी आश्रम में घुस रहा है।" दिल्ली दरबार धीरे से फुसफुसाये, "लड़के की शादी करके यह इतना मायूस क्यों है?" सुमन दरबार के कान में फुसफुसाये, "सर, शादी में काफी

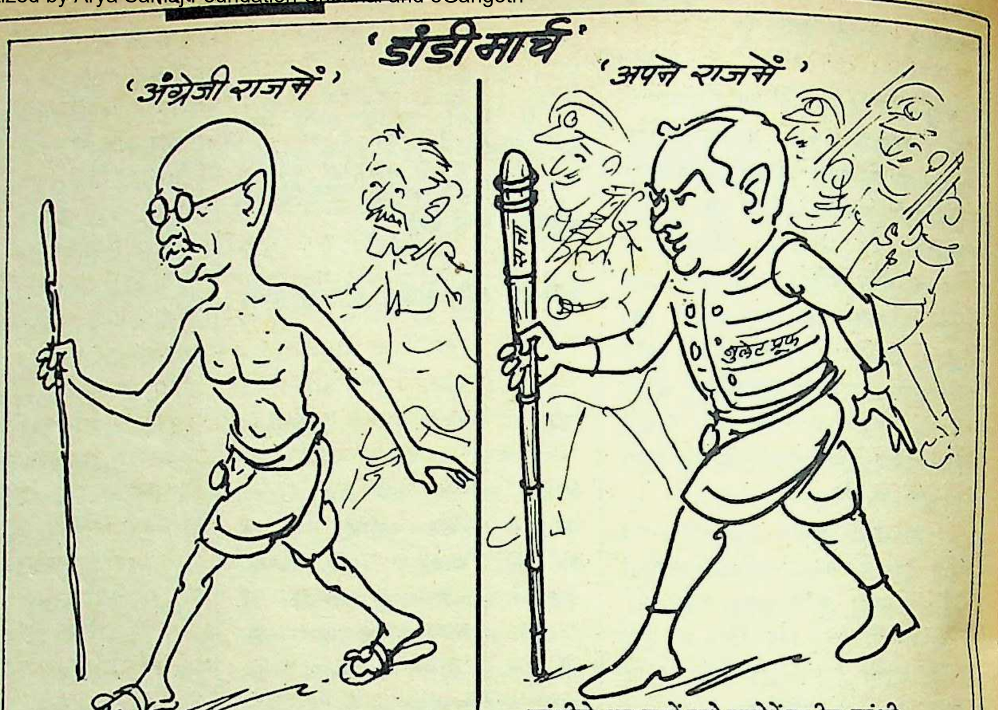

गांधीके आश्रममें कडे पहरेमें राजीव गांधी

'आज' से साभार

चक्कर है। दाढ़ी वाले की ठकुराहट पर बट्टा लग गया है। इसीलिए गुमसुम है।" सुमन और आगे फुसफुसायें कि इसी बीच दरबार ने टोक दिया, "चुप रहो डायलाग सुनने दो...।"

...रामकृष्ण हेगड़े ने बीजू पटनायक को इशारा किया, तो वह तमतमाते हुए चन्द्र शेखर की तरफ बढ़े—"तुम जनता पार्टी को क्या अपनी बपौती समझते हो, मैं पूछता हूं कि अध्यक्ष पद क्यों नहीं छोड़ते?" चन्द्र शेखर ने बीजू को कुरसी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, "मैं अध्यक्ष लड़ कर बना हूं। तुम भी लड़ कर छीन लो। मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन यह सोच लो कि तुममें लड़ने का दम है? तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो सुब्रह्मण्यम स्वामी का हुआ था।" स्वामी का नाम आते ही मधु दंडवते पिल लिये, "आज वही स्वामी तो तुम्हारी नाक का बाल बना हुआ है। हम सब पराये हो गये और लोकदलीय तुम्हारा सगा हो गया। अजीत सिंह को अगर तुम अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे, तो देवी लाल नहीं आयेगा।" चन्द्र शेखर ने अनमने मन से जवाब दिया, "न आये देवी लाल। मुझे उससे क्या लेना देना। अजीत सिंह आ जायेगा, तो जनता पार्टी यूपी और बिहार में तीसरे नम्बर से तुरंत पहले नम्बर की 'अपोजीशन' हो जायेगी। उसके बाद देवी लाल नाक रगड़ेंगे।" हेगड़े ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, "अगर अजीत सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, तो वीपी सिंह के आने में भी अड़चन होगी। नेताजी जरा सोच-विचार कर लो।" चन्द्र शेखर ने हेगड़े पर हल्ला बोल दिया, "तुम क्यों नहीं अध्यक्ष बन जाते!" हेगड़े ने लजाते हुए कहा, "नेताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुरसी मुझसे ऐसी चिपकी हुई है कि छुड़ाये नहीं छूटती। अगर दोनों कुरसियों की टांगें बांध कर एक साथ कर दी जायें, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।" चन्द्र शेखर ने तपाक से हेगड़े को जवाब खींचकर मारा, "तुम्हें परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत परेशानी है। जिन्दगी भर हम लोग एक पद, एक आदमी का नारा बुलंद करते रहे। अब उसी पर समझौता कर लें। हेगड़े यह नहीं हो सकता है। मुझे मुंह छिपा कर नहीं चलना है।" चन्द्र शेखर ने उसके बाद अपनी मुड़िया अपनी दाढ़ी में छिपा ली। हेगड़े फिर चन्द्र शेखर के करीब हुए, "वह अपनी मेनका गांधी को लेने में तो कोई अड़चन नहीं है?" चन्द्र शेखर ने कनखियों से हेगड़े को देखा और मुस्करा दिये, "अब तो मेरी दाढ़ी से तुम्हारी दाढ़ी ज्यादा खिचड़ी दिखायी देने लगी है। और कुछ न हो, मुझे खिचड़ी दाढ़ी का खयाल रखना ही पड़ता है।" हेगड़े नरम पड़ गये। जब लोगों ने देखा हेगड़े नरम होते जा रहे हैं, तो भौंड़सी का भारत यात्रा आश्रम सूना होने लगा। इतने में अजीत सिंह लोकदलीय बिल से निकले और उचक कर बलियाटिक दाढ़ी पर चिपक गये। चन्द्र शेखर ने अपनी दाढ़ी पर कम और राजपूताना मूंछों पर ज्यादा ताव देना शुरू कर दिया। ...फिल्म देखते-देखते अचानक दिल्ली दरबार का हाथ भी अपनी मूंछों पर चला गया। हाथ को जब मूंछ नहीं मिली, तो झुंझलाये, "मेरे मूंछें क्यों नहीं हैं? मैंने भी प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस में शामिल किया है, मेरे मूंछ लगाओ..." दरबार की खीझ से सारे लोग हड़बड़ा गये। सुमन दुबे ने फिल्म बीच में ही रोक कर, बिजली जला दी। अंधेरे का मौका पा कर सारे दरबारी दिल्ली दरबार के शाही पलंग पर जम गये थे। इसको देखकर दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये, "अंधेरे का फायदा उठाकर तुम लोग मेरे शाही पलंग पर आरामफरमा हो गये...।" दरबार की दहाड़ से सारे दरबारी चूहों की तरफ फुदक-फुदक कर कूद लिये, तभी पनिक्कर, गुलाम नबी, आस्कर ने आगे बढ़कर अदब के साथ दिल्ली दरबार के हुजूर में अर्ज किया, "सरकार हम लोग अभी नाबालिग हैं। इसलिए हम लोगों के मूंछों का सवाल ही कहां पैदा होता है।" दरबार फिर भी मूंछों को लेकर ऊहापोह में फंसे हुए थे, तभी चुपचाप पहुंचे भगतजी ने आगे बढ़कर कहा, "जी सरकार हम सभी लोग नाबालिग हैं। देखिए, मेरे चेहरे पर भी मूंछें कहां हैं।" दिल्ली दरबार ने भगतजी के चेहरे को गौर से देखा। जब संतोष नहीं हुआ, तो दिल्ली दरबार ने भगतजी की नाक के नीचे उंगलियां फेर कर पक्का यकीन किया कि दरबारी सच ही बोल रहे हैं। उसके बाद दिल्ली दरबार को पूरा संतोष हो गया कि वे लोग सचमुच ही नाबालिग हैं।

दिल्ली दरबार संतोष की गहरी सांस ले ही रहे थे कि तारिक अनवर सेवा दल की पूरी प्लाटून लेकर घुस आये। गुलाम ने तारिक को दिल्ली दरबार की तरफ मुखातिब होने से रोक लिया, "अबे तारिक अब तू यह सेवा दल की कवायद क्यों कराता फिर रहा है। तुम्हें तो बिहार में गुल्ली-डंडा खेलने के लिए दिल्ली दरबार ने हुकुम दिया है।" तारिक ने गुलाम के पंजों से अपना कालर छुड़ाते हुए, दूर से ही दिल्ली दरबार की तरफ मुखातिब होकर कहा, "हुजूर, वह आपके लिए मेरे सेवा दल की ओर से एक बिलकुल नया 'आइडिया' आया है।" इतने में ही आस्कर और पनिक्कर की मदद से गुलाम नबी ने तारिक को पूरी तरह धकिया कर बाहर कर दिया। गुलाम बोले, "बोलो, क्या आइडिया है। तुम अब सूबाई नेता हो। इस तरह दरबार में सीधे घुसने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। मुझे बताओ क्या आइडिया है?" तारिक ने गुलाम की चिरौरी की, "मुझे दिल्ली दरबार के सामने ले चलो। मैं वहीं आइडिया बताऊंगा।" इस पर पीछे से आस्कर ने तारिक पर अपना हलब्बी हाथ दे मारा। जैसे ही तारिक पछाड़ खाकर गिरे, तो उनके सीने पर गुलाम नबी चढ़ बैठे। तारिक की जब जान पर बन आयी, तो उनके मुंह से 'आइडिया' फूटने लगा। जब गुलाम ने पूरा 'आइडिया' हासिल कर लिया, तो तारिक के सीने पर से उठते हुए कहा, "अबे तारिक आइडिये का खाना सबके नसीब में नहीं होता है। अब यह आइडिया मैं दिल्ली दरबार को दूंगा और उसे अपनी 'होम मिनिस्टरी' पक्की करने के लिए 'कैश' कराऊंगा। देखूं, यह बूटा सिंह अब कितने दिन इस होम मिनिस्टरी में रहता है।" तारिक जब ओझल हो गये, तो गुलाम दिल्ली दरबार के करीब पहुचकर 'आइडिया' फुसफुसाने लगे।

> साबरमती आश्रम से जब दांडी मार्च चलेगा, तो यह बलियाटिक अपनी दाढ़ी नोचने लगेगा। जब दाढ़ी नुचेगी, तो वह कंप्यूटरी छोकरा अजीत सिंह दाढ़ी से निकल भागेगा। बस हमारा काम चल जायेगा। अजीत सिंह को हम लोग दरबार में कोई कंप्यूटर चलाने की नौकरी दे देंगे। सर, दूसरी ओर हम लोग समुंदर में नमक बनवायेंगे और सारे लोगों को नमक चटा देंगे।

गुलाम नबी कह रहे थे, "सर, साबरमती आश्रम से जब दांडी मार्च चलेगा, तो यह बलियाटिक अपनी दाढ़ी नोचने लगेगा। जब दाढ़ी नुचेगी, तो वह कंप्यूटरी छोकरा अजीत सिंह दाढ़ी से निकल भागेगा। बस हमारा काम चल जायेगा। अजीत सिंह को हम लोग दरबार में कोई कंप्यूटर चलाने की नौकरी दे देंगे। सर, दूसरी ओर हम लोग समुद्र में नमक बनवायेंगे और सारे लोगों को नमक चटा देंगे। उसके बाद कोई नमकहरामी नहीं करेगा। सर, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो यह होगा कि आप बहुत 'बोर' हो रहे हैं, इसलिए आपको दांडी मार्च का एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। उससे आपकी 'बोरियत' दूर होगी।" दिल्ली दरबार इस 'आइडिये' को सुनकर चहक उठे। भगतजी की ओट में खड़ी शीला दीक्षित ने जैसे ही दिल्ली दरबार का इशारा पाया, वह 'समरसाल्ट' लगाकर 'दांडी मार्च' की तैयारी के लिए अहमदाबाद पहुंच गयीं। आस्कर ने फौरन दरबार के भोंपुओं से एलान शुरू करवा दिया, "जिनको मंत्रिमंडल में कुरसी चाहिए या राज्यसभा का टिकट, वे फौरन से पेश्तर दांडी मार्च में शामिल होने के लिए अपने-अपने 'पावर शूज' के साथ साबरमती आश्रम पहुंचें। सारा दरबार १२ मार्च को दांडी मार्च के लिए अहमदाबाद कूच कर गया।

—दरबारी लाल

अशोक सेन निकाले जायेंगे

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के मतभेद कांग्रेस-इ से इतने तीव्र होते जा रहे हैं कि वह किसी भी समय पार्टी से निकाले जा सकते हैं। वह अपनी तरफ से इंका को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको दल-बदल कानून के तहत लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा।

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में मार्क्सवादियों ने इंका को बहुत बुरी तरह से पराजित किया है। इससे बंगाल के वामपंथी मोर्चे के घटकों में जहां एक ओर भारी असन्तोष फैला, तो दूसरी ओर कांग्रेस-इ के प्रदेशीय अध्यक्ष प्रियरजंन दास मुंशी को लेने-के-देने पड़ गये। मुंशी ने इस संबंध में राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दे मारा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में मार्क्सवादियों ने बड़े पैमाने पर 'धांधली' की है। लेकिन इसी दौरान अशोक सेन कलकत्ता में मुखर हो उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री ज्योति बसु से भेंट करके यह बयान दे मारा कि "पंचायत चुनाव में मार्क्सवादियों की तरफ से कोई धांधली नहीं हुई है।" अशोक सेन के इस बयान को दिल्ली में बहुत गंभीरता से लिया गया दिल्ली में जानकार सूत्रों का कहना है कि अशोक सेन ने बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से पूरी तरह सांठगांठ कर ली है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार अशोक सेन कलकत्ता के उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और बंगाल का वामपंथी मोर्चा उनको अपना समर्थन देगा। बताया जाता है कि राजीव गांधी के हाथ अशोक सेन का तैयार किया हुआ एक कानूनी दस्तावेज लग गया है, जिसे सेन बाबू ने तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त करने के लिए दिया था। इसी कारण अशोक सेन को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उसी के बाद से अशोक सेन और राजीव गांधी में शीत युद्ध शुरू हो गया था, जो अब निर्णायक दौर में धीरे-धीरे पहुंच रहा है।

केसरीजी और क्या करते!

अखिल भारतीय कांग्रेस-इ के २४, अकबर रोड स्थित मुख्यालय में तीन महामंत्रियों गुलाम नबी आजाद, आस्कर फर्नांडीस तथा के० वासुदेव पनिक्कर ने आधिपत्य जमा लिया और बाकी महामंत्रियों की हैसियत 'किरायेदारों' जैसी हो गयी है। तीन महामंत्री केदार नाथ सिंह, राम रतन राम तथा नरेश चन्द्र चतुर्वेदी उक्त तीनों महामंत्रियों से बिना पूछे न तो कोई बयान दे सकते हैं और न ही कोई खर्च कर सकते हैं। इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी अकसर महामंत्रियों के खर्चों पर कड़ी रोक लगाकर उन पर अपना रोब गालिब किये रहते थे। लेकिन इधर गुलाम नबी आजाद ने केसरीजी को बिलकुल नकार दिया है। गुलाम नबी आजाद ने २४, अकबर रोड स्थित अपने कार्यालय को सजाने-संवारने में लाखों रुपए खर्च कर दिये। बताया जाता है कि जब केसरीजी को पता चला कि गुलाम नबी आजाद अपने कार्यालय पर लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि बिल का भुगतान कौन करेगा? गुलाम नबी ने कहा कि एआईसीसी करेगी और कौन करेगा? इस पर केसरीजी ने सुझाव दिया कि अच्छा होता कि इस खर्च की पूर्व अनुमति ले ली जाती। इससे गुलाम नबी आजाद, केसरीजी से काफी नाराज हो गये और उन्होंने यह बात पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी के कान तक पहुंचा दी। राजीव गांधी ने इस पर गुलाम नबी से कहा कि अगर केसरीजी बिल पास न करें, तो मुझसे पास करा लेना। केसरीजी को जैसे ही यह पता चला, तो उन्होंने फौरन गुलाम नबी आजाद को फोन करके कहा कि जितने बिल हों, उनको भुगतान के लिए मेरे पास भेज दो। इसी के बाद से केसरीजी ने अपने लेखा विभाग को निर्देश दे दिये कि गुलाम नबी आजाद के किसी बिल को न रोका जाये। जब यह बात अन्य महामंत्रियों को पता लगी, तो उन्होंने भी केसरीजी से अपने बिलों के तुरन्त भुगतान करवा देने की व्यवस्था करवाने के लिए कहा, लेकिन केसरीजी टाल गये। आस्कर और पनिक्कर ने भी राजीव गांधी को रोब-दाब दिखाकर अपने बिलों के भुगतान की तो व्यवस्था करा ली, लेकिन बेचारे के०एन० सिंह, राम रतन राम तथा नरेश चंद्र चतुर्वेदी के बिलों के भुगतान महीनों केसरी के चिड़िया बिठाये जाने का इन्तजार करते रहते हैं।

भला हो भाग्यवान बीवी का

केंद्रीय रेल उपमंत्री महावीर प्रसाद इन दिनों इस बात से खास परेशान हैं कि जब वह दिल्ली से बाहर किसी यात्रा पर जाते हैं, तो रेल अधिकारी उनके लिए ट्रेन में विशेष 'सैलून' की व्यवस्था क्यों नहीं करते। इसके लिए उपराज्यमंत्रीजी रेल अधिकारियों से कई बार कह चुके हैं, लेकिन सब-के-सब कान में तेल डाले बैठे हैं।

दूसरी ओर रेल अधिकारी कहते हैं, "महावीर प्रसादजी के दूसरे फालतू कामों से हमें छुट्टी मिले, तो हम उनके लिए सैलून की व्यवस्था करें, क्योंकि आये दिन गोरखपुर में उनका कोई-न-कोई रिश्तेदार या घरेलू सामान ट्रेन से दिल्ली स्टेशन पर आता है।" रेलगाड़ी का मुहकमा संभालने के फौरन बाद महावीर प्रसाद दिल्ली से लखनऊ आये, तो अपने साथ राजधानी से पूरी प्रेस पार्टी लाये। जिन-जिन समारोहों में वह गये, अफसरों का कारवां तो साथ था ही, प्रेस पार्टी को भी साथ ले गये। लेकिन महावीर प्रसाद तब और ज्यादा झल्लाये जब अगले दिन समाचार पत्रों में उनकी एक लाइन की भी खबर नहीं छपी। बात दरअसल यह थी कि जब-जब पत्रकारों ने उनसे रेल विभाग की कोई जानकारी चाही, तो उनका रटा-रटाया उत्तर था, "अभी मैं विभाग का कोई काम नहीं देख रहा हूं, जब सिंधिया से कुछ काम मिलेगा तब खबर दूंगा।" इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे कहा, "लगता है गोरखपुर की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। इसी कारण वहां से एक मुख्यमंत्री बना औरदूसरा रेल उपमंत्री हो गया।"

महावीर प्रसाद ने झट बात काटी, "नहीं-नहीं, गोरखपुर की मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी पत्नी बड़ी भाग्यवान है। वह जब जिंदगी में पहली बार गांव से शहर (गोरखपुर) आयी थी, तो मैं एम०पी० बन गया। दूसरी बार वह गांव से मेरे साथ वाराणसी गयी, तो अगले ही दिन मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। भला हो इस भाग्यवान बीवी का कि तीसरी बार जब वह गांव से मेरे साथ लखनऊ आयी, तो अगले ही दिन मैं केंद्र में उपमंत्री बन गया।

"इस समय भाभीजी कहां हैं?"—उसी पत्रकार ने सवाल किया। "गांव में, अब तक गांव से वह तीन ही बार बाहर निकली है।" महावीर प्रसाद का जवाब था। "फिर तो आप उन्हें एक बार दिल्ली जरूर लायेंगे!" कई पत्रकार एक साथ बोल उठे। "हां लाऊंगा।" इसी के साथ कुछ सोचते हुए बोले, "लेकिन 'वह' बनने के लिए नहीं, जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं।" ■

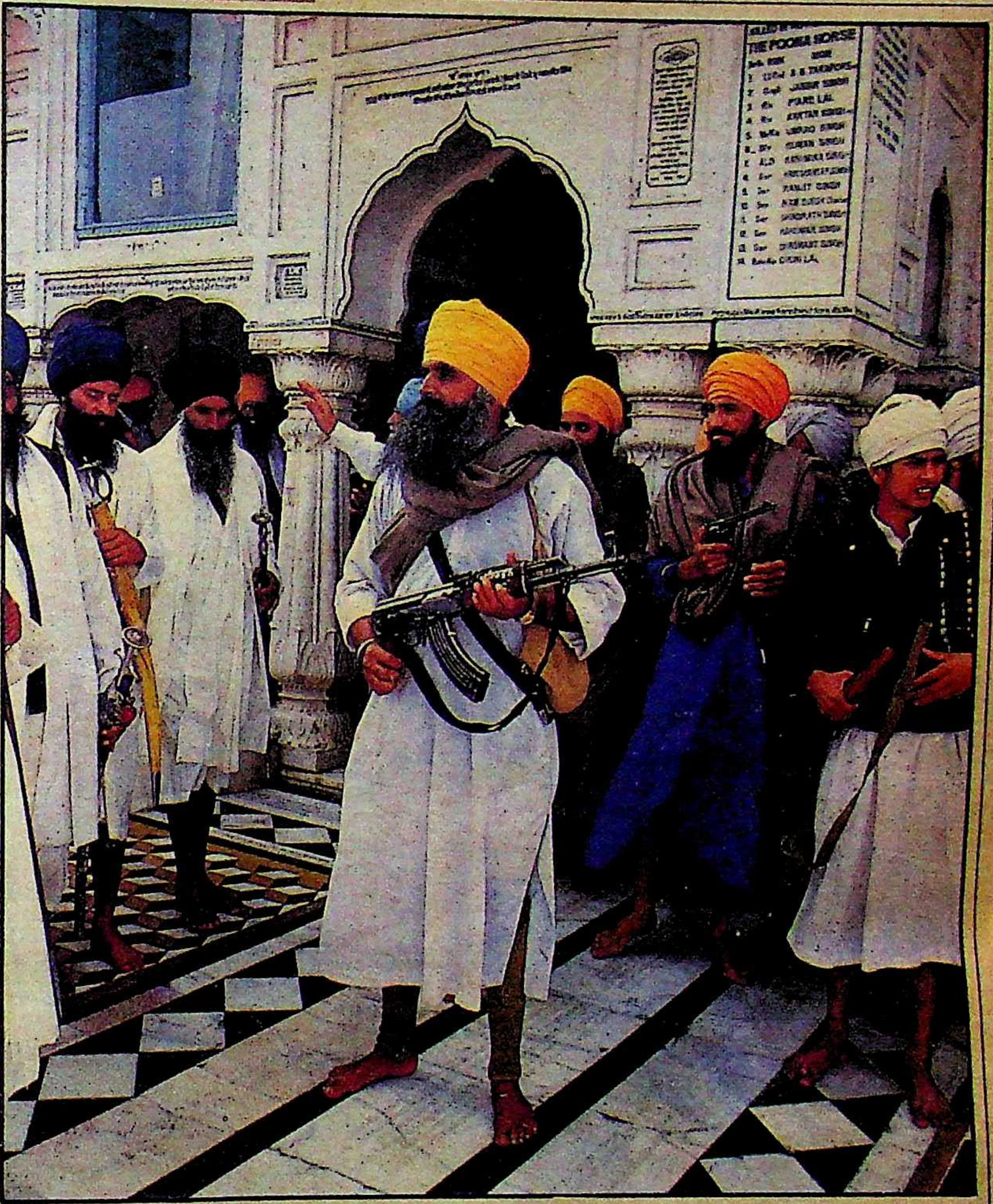

गत १० मार्च को जरनैल सिंह भिंडरांवाले के भतीजे भाई जसबीर सिंह रोड़े को अकाल तख्त का नया जत्थेदार नियुक्त किया गया। वह अब तक नियुक्त जत्थेदारों में सबसे युवा (३४ वर्ष) हैं। यद्यपि 'पूरन आजादी' जैसी बातें अवश्य हो रही हैं, लेकिन फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि नये जत्थेदार का भावी रुख क्या होगा? इतना तय है कि वह उग्रवादियों को प्रिय रहे हैं और जिस समय उनका चुनाव हो रहा था, उस समय अत्याधुनिक हथियारों से लगभग ४०० चक्र गोलियां चलाकर उनके समर्थकों ने खुशियां व्यक्त की थीं। इस समय स्वर्ण मंदिर पूर्णतया उसी तरह से हथियारबंद उग्रपंथियों के कब्जे में है, जैसे भिंडरांवाले के समय में था। इन उग्रवादियों का मकसद है, अंधाधुंध हत्याएं करके सरकार को अपने साथ समझौते के लिए विवश करना। केंद्र सरकार ने 'आपातकाल' का हथियार भी अपने हाथ में ले लिया है। देखना है, अब आगे पंजाब क्या मोड़ लेता है।

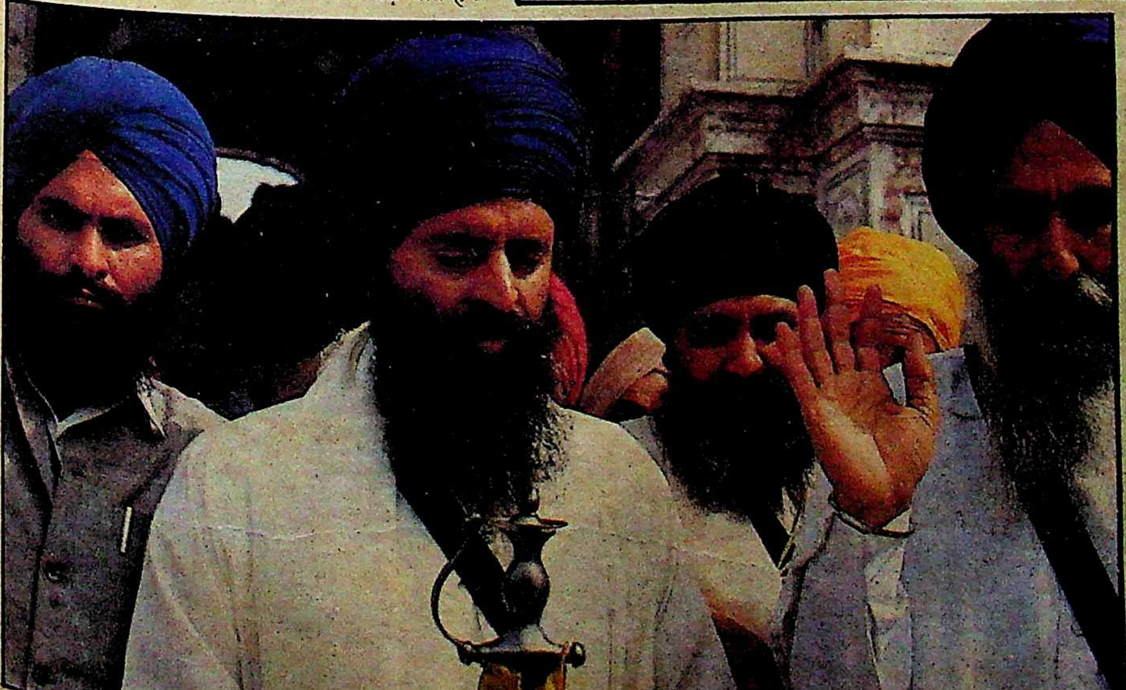

छाया :
सुनील सक्सेना

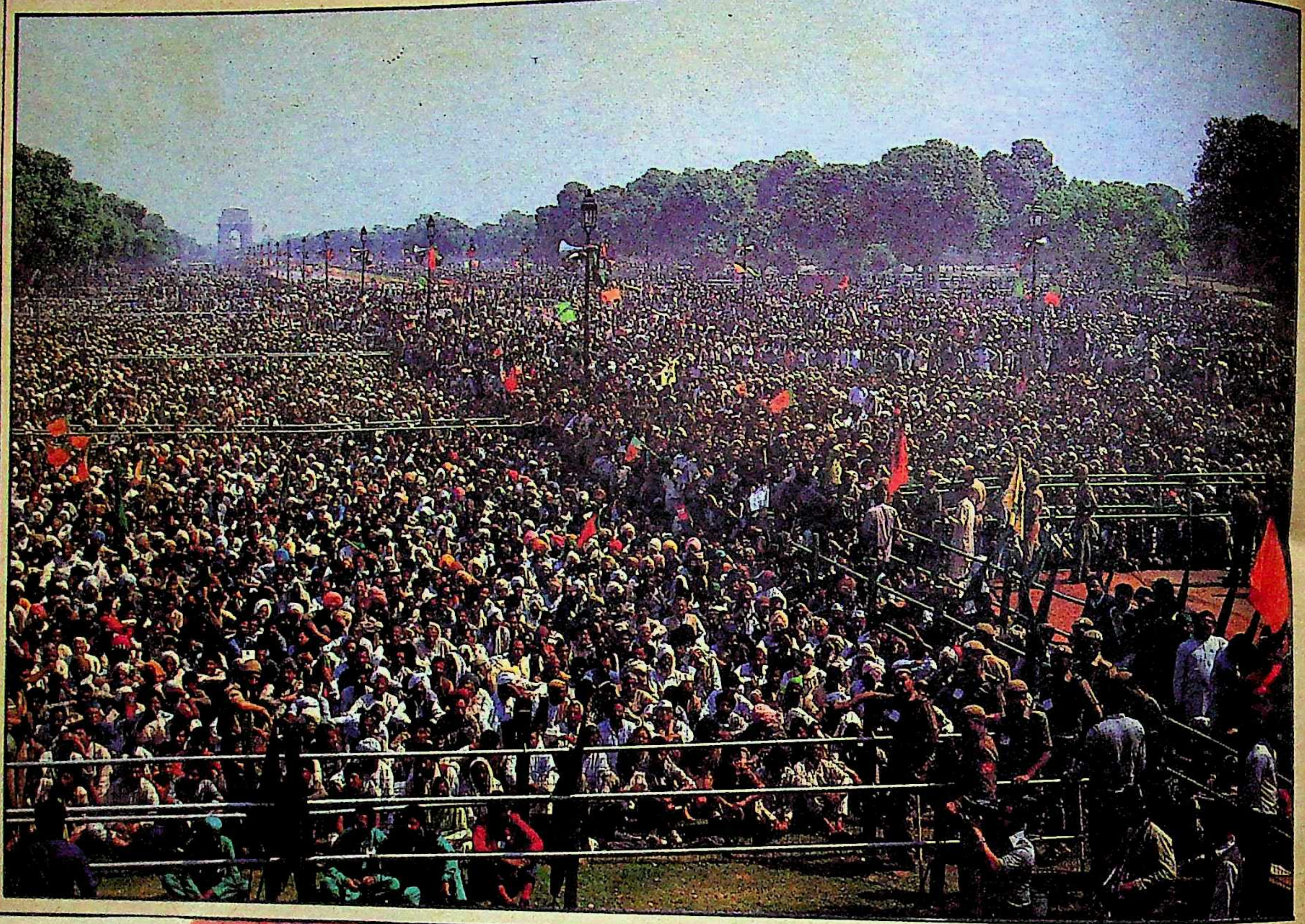

९ मार्च को लोकदल-ब और भाजपा ने दिल्ली के बोट क्लब पर विशाल रैली का आयोजन करके एक बार फिर साबित किया कि हरियाणा में उसकी पकड़ ज्यों-की-त्यों है। इस रैली को रामकृष्ण हेगड़े और एन०टी०आर० के अतिरिक्त देवीलाल, अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संबोधित किया। रैली में नेताओं ने राजीव सरकार को हटाने का आह्वान किया।

छाया :
निर्मल वैद

छाया :
वाई०के० जालान

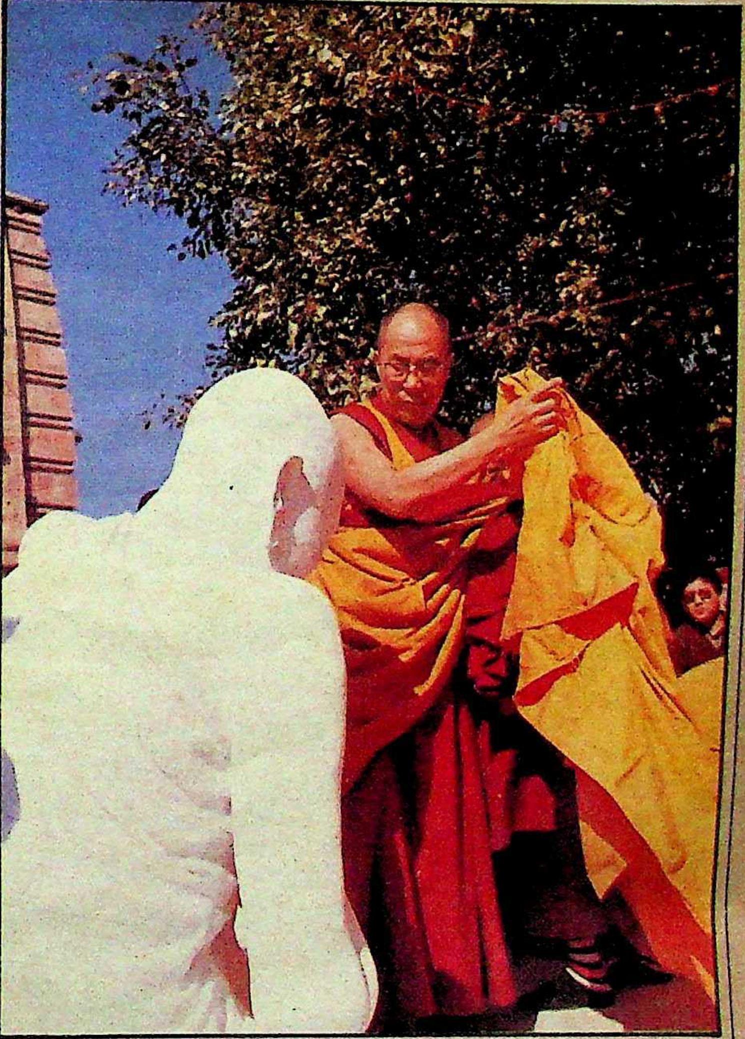

तिब्बतियों के धर्मगुरु परमपावन दलाईलामा ने पिछले दिनों सारनाथ (वाराणसी) स्थित मूलगंध कुटी विहार परिसर में बोधिवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के पांच आदि शिष्यों—कोडिन्य, भदक, महानाम, आवंजित और वाम की प्रतिमाओं के साथ अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक विशेष समारोह में की। इन प्रतिमाओं को एक बड़े गोल मंच पर स्थापित किया गया है। प्रतिमाओं के अनावरण के समय पूरा मूलगंध कुटी विहार परिसर चीन, बर्मा, जापान, नेपाल, स्विट्जरलैंड, अमरीका से आये बौद्ध भिक्षु और बौद्ध श्रद्धालुओं से भरा पड़ा था।

१० लाख रुपए की लागत से बनी इन प्रतिमाओं के निर्माण का भार भारतीय मूल के बर्मा निवासी बौद्ध भिक्षु यू० नंदाचार्य ने उठाया। प्रतिमा के निर्माण हेतु बर्मा से प्लास्टर आफ पेरिस का सांचा बनवाया गया था, जिस पर १ लाख ७० हजार रुपए खर्च हुए हैं। ये सांचे वायुयान से भारत लाये गये थे।

छाया :
क्लाउन

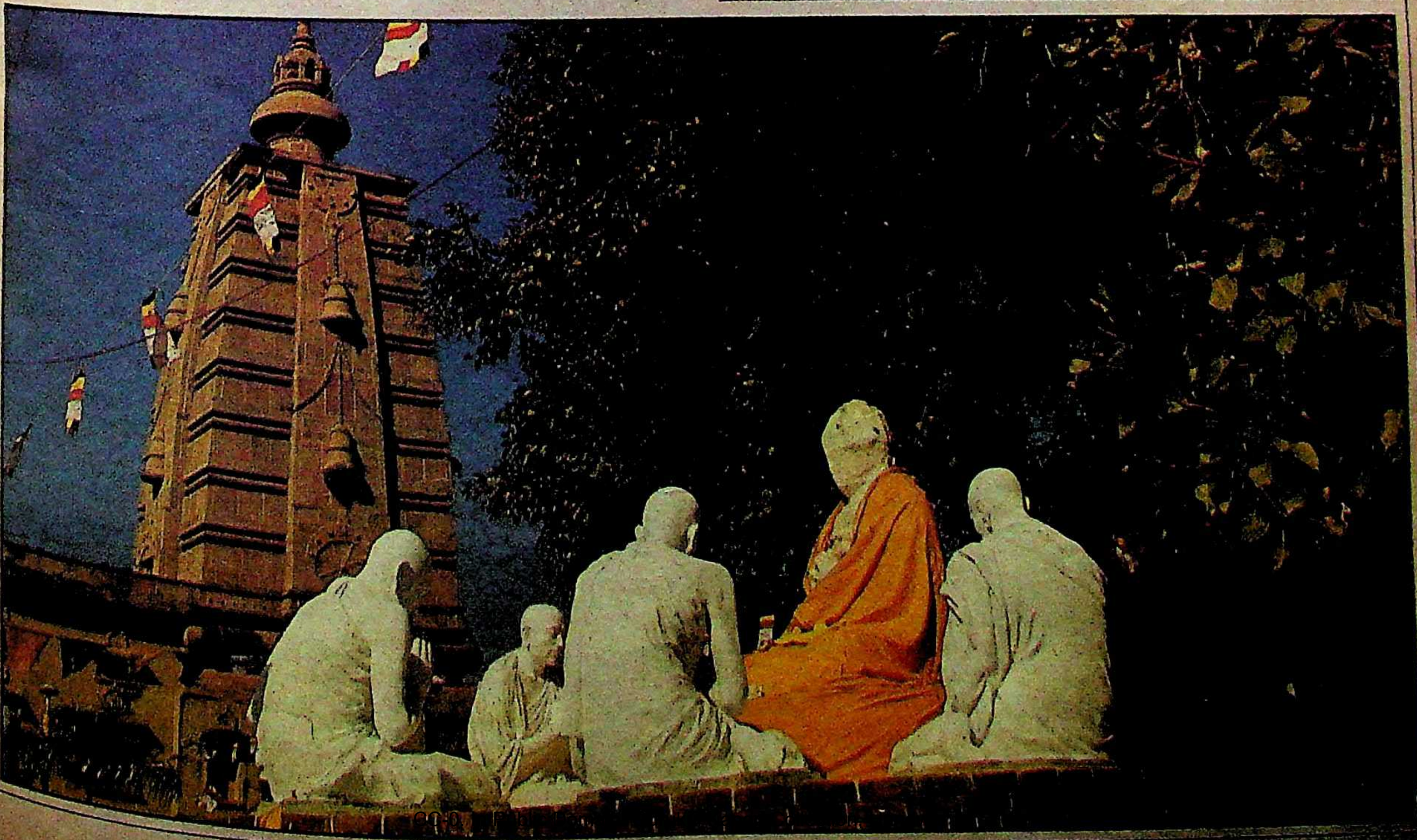

छाया : क्लाउन

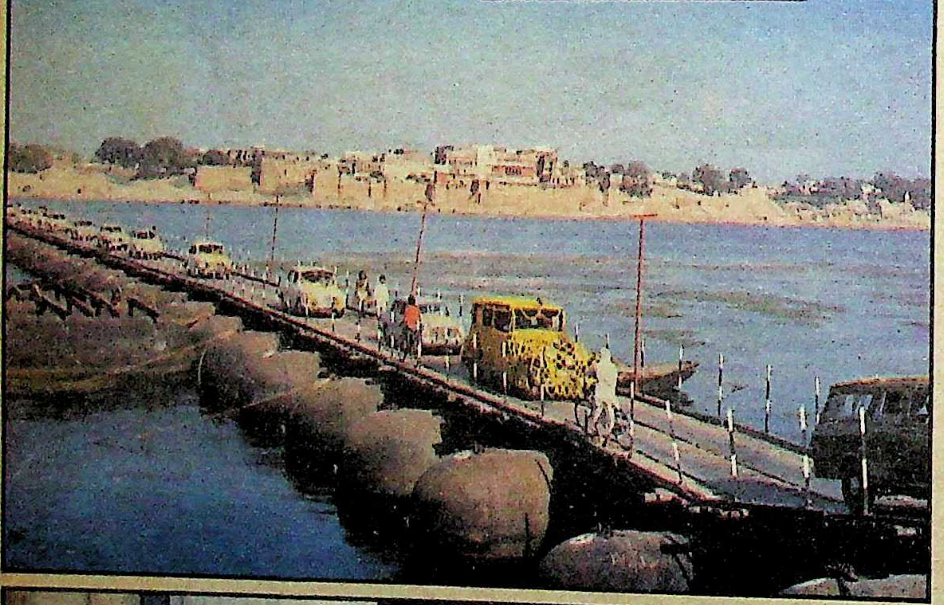

९ मार्च का दिन सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मौज-मस्ती की नगरी काशी के जनजीवन में एक विशेष पर्व के रूप में आया। यह दिन काशीवासियों के लिए लुप्त होती एक परंपरा और रीति-रिवाज को पलकों पर बिठाने का दिन था। इस दिन पूर्व काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के एकमात्र पुत्र युवराज अनंत नारायण सिंह का विवाह शाही रीति-रिवाज के आवरण में समस्तीपुर के कुबौली निवासी तथा पटना के डिप्टी कलेक्टर राजीव लोचन प्रसाद सिन्हा की कनिष्ठ पुत्री अनामिका के साथ संपन्न हुआ। यद्यपि यह थी, तो सामंती ढंग की शादी, लेकिन इसमें एक तो धन का अश्लील प्रदर्शन नहीं था और दूसरे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। शायद इसीलिए बनारस के लोगों ने इस शादी में उछाहभरी सक्रियता दिखायी।

रामनगर किले से निकली वर-यात्रा में युवराज १९२७ माडल की आठ सिलिंडर वाली कैटलग कार में सवार होकर पीपे के पुल से पुराने सरकिट हाउस पहुंचे। फिर वहां से वर-यात्रा विवाह स्थल (नदेसर पैलेस) की ओर चल पड़ी। यात्रा में सबसे आगे एक घोड़े पर बनारस स्टेट का ध्वज पकड़े एक सेवक चल रहा था। पीछे हाथी दांत से बनी बग्घी पर पूर्व काशी नरेश विभूति नारायण सिंह चल रहे थे। पूर्व काशी नरेश जिस हाथी दांत की बग्घी में सवार थे, उसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। बग्घी के पीछे हाथी पर सोने के हौदे पर युवराज सवार थे। वर-यात्रा में एक हाथी पर स्वर्ण निर्मित 'राज चिह्न' की बड़ी आकृति भी थी।

द्वार-पूजा की औपचारिकता के बाद युवराज को आकर्षक पंडाल में निर्मित मंच तक ले जाया गया, जहां देश के कोने-कोने से आये पूर्व रजवाड़ों आदि ने युवराज को आशीर्वाद दिये।

डिग्री उद्योग

यों तो विद्यार्थी जीवन कठिन तपस्या और अनुशासन का जीवन है, बस आजकल थोड़ा सा अंतर आया है, तो उसके चाल-ढाल और रहन-सहन में। फिर भी बेचारे को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पढ़ना नही पड़ता तो क्या हुआ, पास होने के लिए उसे कितनी तिकड़म लगानी पड़ती है, कितने तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। देखिए न बिचारा पढ़ने में व्यर्थ मेहनत न कर घर में टीवी पर जमा ही रहता है, तरह-तरह के ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रमों से कुछ-न-कुछ तो अपनी बुद्धि में इजाफा करता ही है। घर से बाहर भी सिनेमा जाना, क्लबों, काफी हाउस, रेस्टोरेंटों, कल्चरल इवनिंग में थोड़ा समय जाया कर लेता है। घूमता-फिरता है, मिलता-जुलता है। अब अगर थोड़ा नेतागिरी कर लेता है, तो क्या बुरा करता है। उसे भी कल इम्तिहान में बैठना है, गुरुओं के चरण नहीं चापेगा, नेताओं से नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा। इम्पार्टेंट सवालों का पता कैसे चलेगा? फिर रात-रात भर जागकर चिट बनाना। एक आध छुरे-कट्टे का इंतजाम करना। कापियों को बाहर से लिखवाने की व्यवस्था करना। कितनी ही झंझटें उठानी पड़ती हैं तब जाकर परीक्षा रूपी वैतरणी से ऊबर पाता है। बुरा हो शिक्षा के उन पहरुओं का जिन्होंने कालेज, युनिवर्सिटी वगैरह में प्रवेश परीक्षा का रोग शुरू कर दिया है। क्या-क्या करें विचारे आजकल के एकलव्य! लेकिन विद्या की अरथी ढोने वाले ऐसे ही विद्यार्थियों की झंझटों को दूर करने के लिए बिहार के कुछ भलेमानुसों जिनमें बिहार स्कूल परीक्षा परिषद के लोग भी शामिल हैं, ने एक डिग्री-मार्कसीट उद्योग ही कायम कर लिया है। किसी तरह का सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं, बस ५०० रुपए से १००० रुपए में किसी भी परीक्षा की सनद या मार्कसीट उपलब्ध है, उनके पास। और जब देश को हांकने वाले करोड़ों की दलाली ले सकते हैं, तो ये विचारे क्या ५००-१००० में भी गये-गुजरे हैं! इस बेरोजगारी के दौर में विचारों ने आखिर में नौकरी दिलाने की भी तो गारंटी ले रखी है, क्या बुरा है! न जाने सरकार उसे कुटीर उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे देती? जबकि हजारों की संख्या में लोग इस डिग्री उद्योग में लगे हुए हैं। उसी का सुफल है कि पटना विश्वविद्यालय के बी०एन० कालेज में ८० फीसदी प्रवेशार्थियों ने फर्जी मार्कसीट जमा की है, लेकिन जिलाधीश ने कालेज वालों से ऐसे प्रत्याशियों की जब सूची मांगी, तो उन्हें निराश ही होना पड़ा। मजे की बात तो यह है कि इन लायक प्रत्याशियों में बहुतेरे वहां के बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अफसरों और कालेज के प्राध्यापकों के वार्ड हैं। जब से उनको पोल-पट्टी खुलने का भय हुआ है तब से ये कालेज के अधिकारियों पर उन फर्जी मार्कसीटों-सनदों को वापस करने के लिए तरह-तरह के दबाव डाल रहे हैं। आगे क्या होगा, यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण की ऐसी धरती को प्रणाम किये बिना मन नहीं मानता।

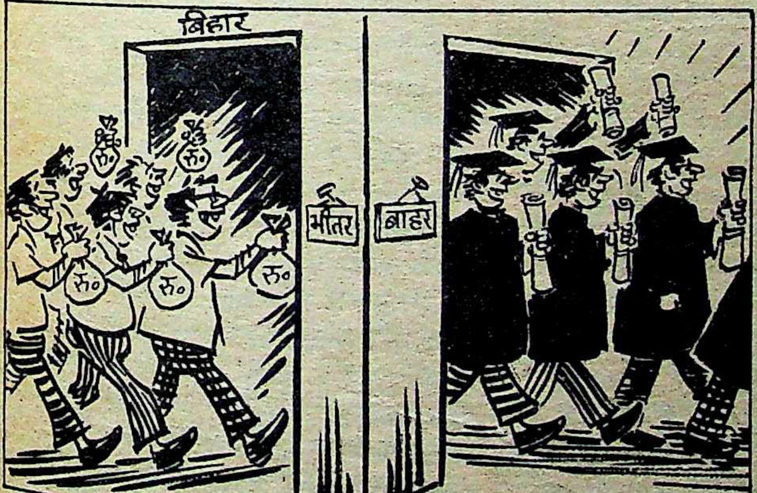

चलती-फिरती मौत

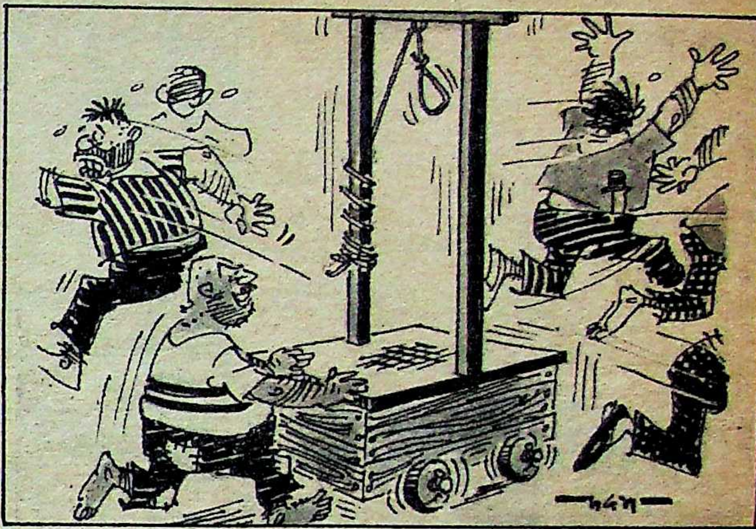

२१वीं सदी में जाने का ठेका अकेले हमारे देश ने ही थोड़े ले रखा है। सारे मुल्कों को बराबर का हक है। जो मुल्क वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बढ़े-चढ़े हैं, वे तो सूरज-चांद पर जाने और रहने की बात सोचेंगे ही, लेकिन जो विकास की देहलीज पर नया-नया पांव रख रहे हैं, उनका भी तो कुछ-न-कुछ हक बनता ही है। अब अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए न। अब उसने मौत की चलती फिरती गाड़ी की ही ईजाद कर ली है। अपराधियों को मौत देने के तरीकों पर हम चाहे भले बहस-मुबाहसा करते रहें, उसमें क्रूरता के बजाय चाहे भले मानवता की वकालत करें, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने यहां अपूर्व पद्धति का विकास कर ही लिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस गाड़ी की बड़ी चर्चा है। पाकिस्तान सरकार ने यों ही दिखावे के लिए यह गाड़ी नहीं बनायी है, बल्कि जिन अपराधियों को सजा-ए-मौत दी जायेगी, उन्हें सार्वजनिक रूप से इसी चलती-फिरती गाड़ी के फांसी के फंदे पर लटकाया जायेगा ताकि अन्य अपराधियों में इतनी दहशत फैल जाये कि वे अपराध करने का नाम तक न लें। यह गाड़ी प्रांत भर में घूम-घूमकर अपना दायित्व निबाहेगी। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का तो दावा है कि दो-तीन महीनों के अंदर पंजाब प्रांत से डकैती, हत्या और चोरी जैसे अपराधों का समूल नाश किया जा सकेगा। देखना है, इसका क्या नतीजा निकलता है? और उसके नतीजे से प्रभावित होकर कौन-कौन मुल्क पाकिस्तान का अनुकरण करते हैं।

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

वधुओं का निर्यात

अमरीकी युवकों को हिंदुस्तानी कन्याओं में इधर विशेष रुचि पैदा हो गयी है। आजकल पूना इस प्रकार की हवाई शादियों का केंद्र हो गया है। अभी हाल ही 'ब्रुकलिन' नामक एक अमरीकी युवक ने पूना आकर एक ब्राह्मण की सुकन्या से अदालत में शादी की, अपनी नववधू का वीसा बनवाया और उडता बना। आश्चर्य यह है कि ये शादियां हजारों किमी० दूर अमरीका में बैठे हुए संचार प्रणाली (रिमोट कंट्रोल) से तय की जाती हैं, जिससे कुंडली मिलाने वाले पंडितों की रोजी भी खतरे में है। अमरीकी हिंदुस्तानी कन्याओं में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं, पता नहीं चल सका है, देखना है ये 'हवाई शादियां' कितनी सफल होती हैं? अगर ये शादियां सफल सिद्ध हुई, तो बिना दान-दहेज के कौन मां-बाप नहीं चाहेगा कि अपनी लडकियों की शादी कर दे, चाहे भले उसकी लडकी सात समुद्र पार ही चली जाये।

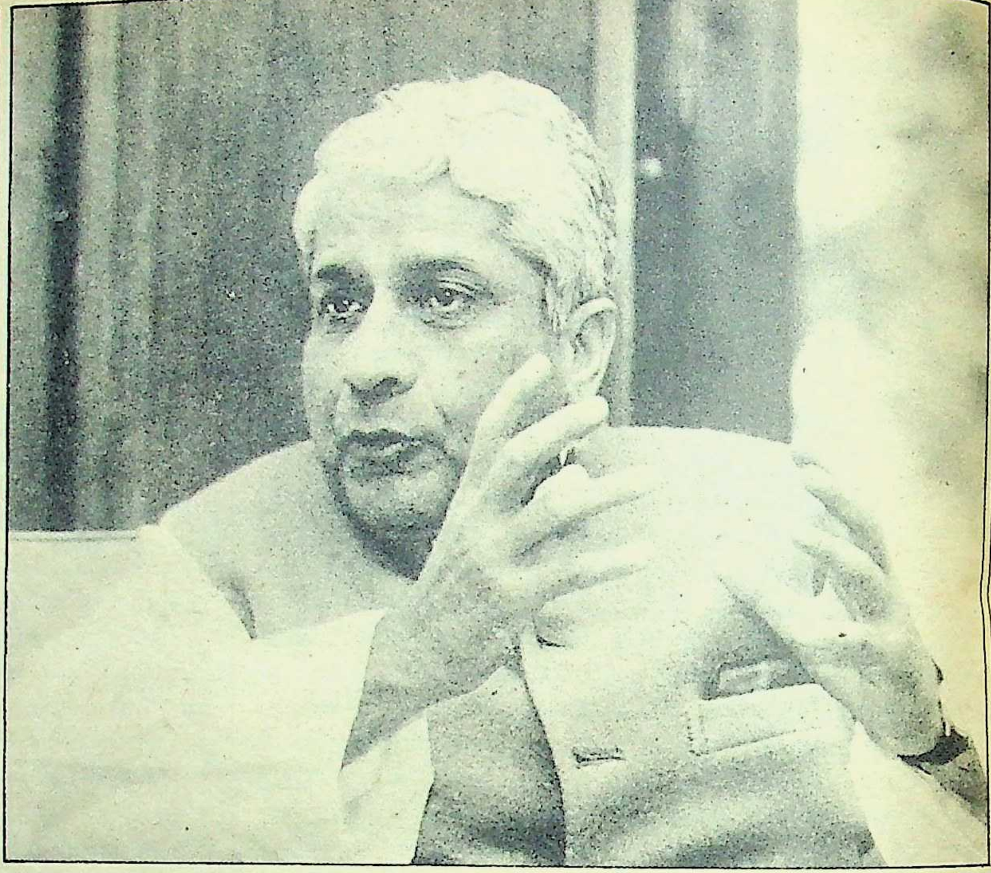

दिनेश सिंह

कांग्रेस को खतरा किसी व्यक्ति से नहीं, अपने आप से है

कालाकांकर के ६३ वर्षीय पूर्व राजा एवं श्रीमती गांधी मंत्रिमंडल के बहुचर्चित कैबिनेट मंत्री दिनेश सिंह गत वर्ष से फेयरफैक्स प्रकरण में सरकारी मोर्चा संभालने के फलस्वरूप पुनः सुर्खियों में हैं। दून स्कूल में शिक्षित और सिविल सर्विस के मार्ग से केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम बार, १९६२ में विदेश विभाग के उपमंत्री के रूप में स्थान पाने वाले पूर्व कालाकांकर नरेश दिनोदिन उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते गये। लेकिन १९६६-६७ में विदेशी मामलों के उपमंत्री, १९६७-६९ में वाणिज्यमंत्री, १९६९-७० में विदेश मंत्री और १९७०-७१ में उद्योग मंत्री रहने वाले दिनेश सिंह का अवसान भी उसी तीव्र गति से हुआ। लगभग १७ वर्ष के वनवास के पश्चात पिछले मंत्रिमंडलीय फेरबदल में प्रधानमंत्री की कृपादृष्टि से जल संसाधन मंत्री बने। प्रतापगढ़ (उ०प्र०) से लोकसभा सदस्य के विषय में आम धारणा है कि उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह से लोहा लेने के पुरस्कार स्वरूप यह पद-प्रसाद प्राप्त हुआ है। राजनीति सहित देश-विदेश के मामलों-मुद्दों में पटु-पारंगत पूर्व राजा से 'माया' की लम्बी बातचीत के *अंश :*

माया: *एक अरसे के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं?*

सिंह: मैं राजनीति से तो बाहर रहा नहीं। राजनीति का मुख्य उद्देश्य है जनसेवा। मैं संसद में भी रहा हूं, इसलिए कोई-न-कोई काम तो करता ही रहा हू। मंत्रीं होने पर कुछ सुविधाएं, साधन ज्यादा हो जाते हैं। उनका उपयोग कर उसी सेवा को बढ़ाता रहूंगा। मुझे प्रधानमंत्री का विश्वास मिला है, इसी की खुशी है।

माया: *आप अनेक वर्षों से विदेश, उद्योग एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान कैबिनेट में आपके अनुभवों का लाभ न उठाते हुए जल संसाधन जैसा सामान्य विभाग आपको सौंपा गया है। ऐसी अटकलें लगायी जा रही हैं कि आगामी फेरबदल में आपके उन अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जायेगा।*

सिंह: विदेश, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालयों में तो मैं काम कर ही चुका हूं। अब नया विभाग एवं नया अवसर मुझे कुछ अलग काम करने के लिए प्राप्त हुआ है। पहले यह मंत्रालय (जल संसाधन) सिचाई विभाग से सम्बद्ध था। प्रधानमंत्रीजी ने इसे नया रूप दिया। अभी तक अनेक बांध, नहरें आदि बनायी गयी हैं, किंतु सिचाई के लिए जल आपूर्ति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जल संसाधन के अंतर्गत यह कमी दूर करने का प्रधानमंत्रीजी ने बहुत बड़ा काम किया है। पानी, प्राण रक्षा और उत्पादन का प्रमुख साधन है। यह बात अतरराष्ट्रीय जगत में स्वीकार की गयी है। हमारे देश में अधिकाश जल या तो बरबाद हो जाता है या फसलों को क्षति पहुंचाता है। हमारी ज्यादातर नहरें कच्ची हैं, जिनमे पानी बहकर या तो फसलों को डुबो देता है या बरबाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में पानी का समुचित उपयोग हमारी प्रगति के लिए परमावश्यक है। अभी तक सिचाई के लिए खेतों में पानी भर दिया जाता था। सिचाई की नवीन प्रणालिया विकसित हुई हैं, इससे कम पानी में फसलों का उपजाऊपन बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा विभाग मामूली नहीं, महत्वपूर्ण है।

माया: *इसका अर्थ है कि इस विभाग की महत्ता बढ़ जाने से आगे भी आप इसी में रहेंगे। किंतु ऐसी अटकलें लगायी जा रही हैं कि बोफोर्स जांच समिति से फारिग होने के बाद जब शंकरानंद वापस आकर अपना विभाग संभाल लेंगे, तो आप अपने किसी पुराने विभाग में पहुंच जायेंगे।*

सिंह: प्रधानमंत्रीजी मुझे जो दायित्व सौंपेंगे, उसे मैं निभाऊंगा।

माया: *इतने वर्षों बाद मंत्रिमंडल में आपको क्यों शामिल किया गया? कहा जाता है कि संसद में वीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा लेने के पुरस्कार स्वरूप आपको यह मंत्री-पद लगभग २० वर्ष बाद प्राप्त हुआ है। इसमें कितनी सचाई है?*

सिंह: मैंने वीपी सिंह के खिलाफ कोई मोर्चा

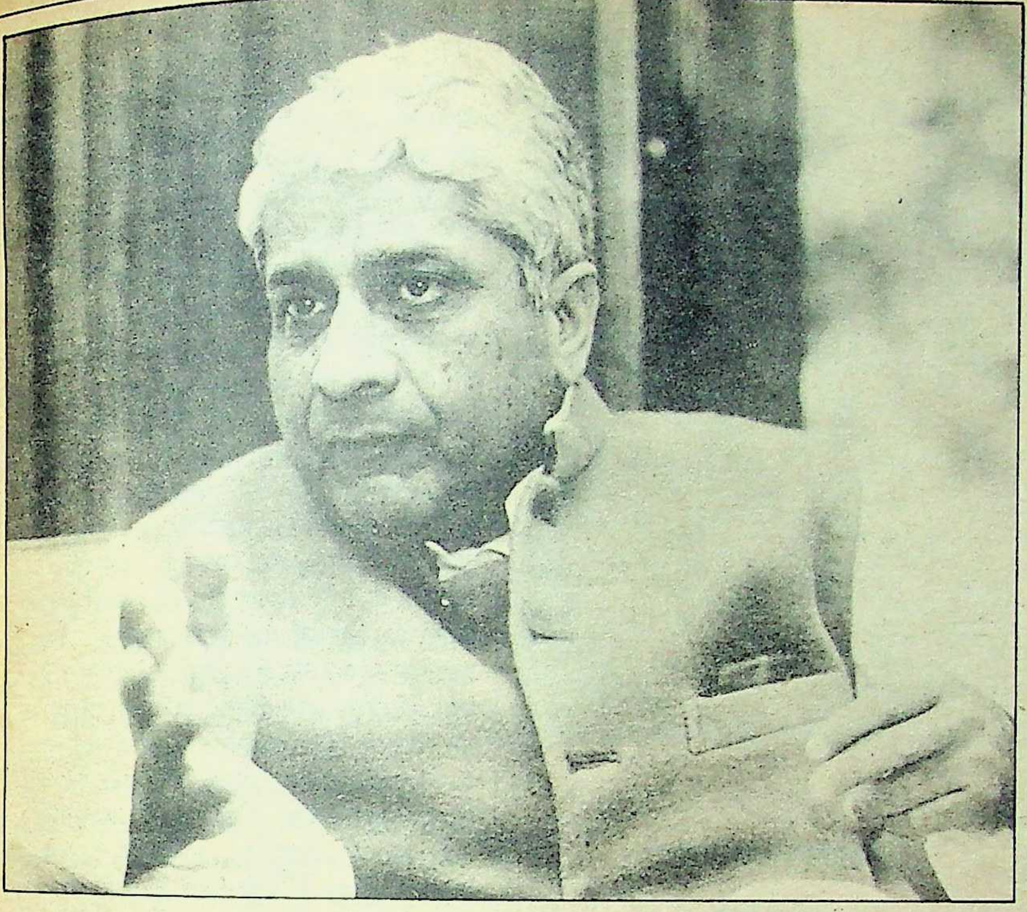

> वीपी सिंह से लड़ाई या समझौते का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने संसद के अंदर जो भाषण दिया था, उसमें वीपी सिंह का नाम तक नहीं लिया था। यह लड़ाई व समझौता तो आप लोगों की कल्पना की उपज है। मुझे तो ख़ुशी है कि मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है।

नहीं लिया, इसलिए उसके पुरस्कार का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने फेयरफैक्स कंपनी की नियुक्ति के विषय में सवाल उठाया था कि नियम विरुद्ध उक्त विदेशी एजेंसी को तैनात किया गया और सरकारी गुप्तचर एजेंसियों की सलाह या सहायता की जगह कुछ लोगों के कहने पर ऐसा कदम उठाया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं वीपी सिंह ने अपने ऊपर ली थी। ऐसी सूरत में यह कहना कि मैंने वीपी सिंह के खिलाफ माहौल तैयार किया और उनकी राजनीति के खिलाफ मुझे काम करने के लिए रखा गया है, सही नहीं है। वीपी सिंह का अपना न तो कोई कार्यक्रम है न नीति, जिससे कि जनता में उनका कोई असर बढ़े। उनका एकमात्र काम कांग्रेस व खासकर राजीव गांधी की आलोचना करना है। इससे मिली लोकप्रियता चंदरोजा है।

माया: ***कहा जाता है कि वीपी सिंह के ठाकुर लाबी पर फैलते प्रभाव की काट के लिए आपको लाया गया है।***

सिंह: जाति के आधार पर राजनीति का सही विश्लेषण नहीं होता है। यह जरूरी है कि हम बड़े दायरे से छोटे दायरे में आते जा रहे हैं। क्षेत्र, भाषा के बाद हम धर्म और जाति के घेरे में घिरते जा रहे हैं। इससे देश का अहित होगा। हमें मिलकर यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार देश, कांग्रेस, और जनता का हित हो। हम जनता को कांग्रेस के कार्यक्रमों तथा नीतियों के विषय में जितनी अधिक जानकारी दे पायेंगे, उतना ही अधिक विपक्ष—चाहे वह वीपी सिंह हों या अन्य—कमजोर होगा।

माया: ***किंतु जातीय समीकरण का पूरा खयाल कांग्रेस कर रही है। मसलन उ०प्र० में वीपी सिंह का सर्वाधिक प्रभाव है और वहां के ठाकुर मुख्यमंत्री को तमाम आरोपों के बावजूद गद्दीनशीं रखा गया है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपको वीपी सिंह के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।***

सिंह: मैं अपने को किसी जाति, वर्ग अथवा क्षेत्र का नेता तो क्या प्रतिनिधि भी नहीं मानता हूं। इस दृष्टि से देश को बांटनें में बड़ा नुकसान होगा। मेरी समझं से जातीय आधार पर सोचने वालों को राजनीति से दूर रखना चाहिए।

माया: ***यह भी कहा जाता है कि पहले तो संसद में आपने वीपी सिंह के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया और बाद में आप दोनों में गुप्त समझौता हो गया। इस बारे में वीपी सिंह से प्रश्न किया गया, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और हंसकर कहा कि तब तो श्रेय हम दोनों को देना चाहिए कि हमने संघर्ष के बाद समझौता कर लिया।***

सिंह: वीपी सिंह से लड़ाई या समझौते का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने संसद के अंदर जो भाषण दिया था, उसमें वीपी सिंह का नाम तक नहीं लिया था। यह लड़ाई व समझौता तो आप लोगों की कल्पना की उपज है। मुझे तो ख़ुशी है कि मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है।

माया: ***इतने समय तक राजनीति से अलग-थलग आप क्यों थे?***

सिंह: राजनीति से नहीं—पद से अलग था। यह सवाल आप पद देने वालों से पूछिए कि मुझे क्यों अलग रखा गया। मेरा कार्य तो चल रहा था, जब पद पर था तब भी और बाहर था तब भी।

माया: ***वर्तमान कंप्यूटरी-सफारी राजनीतिक संस्कृति में आप जैसा पारंपरिक और बुजुर्ग कांग्रेसी नेता क्या अपने को अजनबी नहीं महसूस कर रहा है?***

सिंह: आपने तो अभी मुझे बुजुर्ग कह दिया, जबकि अनेक वयोवृद्ध नेता मौजूद हैं। मैं तो सबसे मिलजुलकर काम करने वाला हूं। इस देश की संस्कृति सबके साथ मिलजुल कर चलने की तथा मध्यम्ममार्गी रही है। हर विचारधारा के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का हमारा आदर्श रहा है। न तो मैं बुजुर्गों और न युवाओं के साथ अपने को अजनबी समझता हूं। मैं सबके साथ मिल कर काम करना चाहता हूं।

माया: ***तब के और अब के राजनीतिक वातावरण में क्या अन्तर लगता है—खासकर शासक दल तथा विपक्ष के तालमेल और मुठभेड़ में?***

सिंह: जब हम लोग राजनीति में आये थे, तब हम युवा थे। तब अनेक बुजुर्ग नेता भी थे। उस समय यह सवाल नहीं उठता था कि अमुक युवा है अमुक बुजुर्ग। पंडित नेहरू की छत्रछाया में हमने काम किया, गांधीजी का आशीर्वाद हमें

प्राप्त था और नेताओं के साथ भी हमने काम किया। फिर आज बुजुर्ग और युवाओं की यह भावना कैसी? यह सही है कि आज वातावरण बहुत बदल गया है। पहले ऐसे नेता थे जो मुक्ति आंदोलन के अंग थे। उनकी अपनी गति और परंपरा थी। उनमें त्याग और देशभक्ति का अपना अनूठा जज्बा था। आज सत्ता उनके हाथ में है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था और उस त्याग के वातावरण से वे नहीं गुजरे हैं। जितने भी आज नौजवान हैं, वे भी उस भावधारा से नहीं गुजरे। संभव है इस नयी पीढ़ी के दिल में देश को आगे ले जाने का इरादा हो और अपना ढंग हो। इसलिए हमको उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक नया युग आ रहा है, उससे हमारा देश क्यों पिछड़ा रहे। नयी तकनीक को अपना कर सदियों की गरीबी मिटाने का उनका संकल्प स्वागत-योग्य है।

माया: क्या आज की राजनीति में कुछ हलकापन नहीं आ गया है—भले ही वह शासक दल हो या विपक्ष?

सिंह: पुरानी परंपरा के अनुसार ऐसा लग सकता है, जिसका आधार था त्याग। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं इसके बजाय आप लोगों का यह खयाल है कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है। लोग अपनी तरक्की के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। यह पहले और अब में एक स्पष्ट अंतर है। किंतु यह एक विश्वव्यापी भावना है। विकसित देशों में आर्थिक नियंत्रण कम होने से व्यक्तिगत हित-साधन की भावना सर्वोपरि है। विकासशील देशों में ऐसा संभव नहीं है। हमें देखना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए सरकार का नियंत्रण अधिक है। जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति होगी, वैसे-वैसे व्यक्तिगत लाभ की विचारधारां सिर उठायेगी। राजनीतिक माहौल ही नहीं बदला है, लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं भी बदली हैं।

माया: विपक्ष के संबंध में आपका क्या विचार है?

सिंह: विपक्ष यहां कभी नीति के आधार पर नहीं रहा है। नीति और विचारधारा कांग्रेस की रही है और कम्युनिस्टों की। बाकी दल कांग्रेस से किसी-न-किसी प्रकार जुड़े रहे हैं और उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं रही है। उनका एकमात्र कार्यक्रम रहा है कि किस प्रकार सरकार को बुरा बताकर अपने को अच्छा साबित करें। विपक्ष की स्पष्ट नीति होती, तो देश आज अधिक मजबूत होता। विपक्ष कांग्रेस की आलोचना तो करता है, किंतु यह नहीं बताता कि कांग्रेस के स्थान पर वह क्या नीति और कार्यक्रम पेश करेगा। इसलिए विपक्ष यहां कमजोर रहा, कमजोर है और कमजोर रहेगा।

माया: पिछले और वर्तमान मंत्रिमंडल और उसकी कार्यशैली में आपको क्या अंतर दिखायी दे रहा है?

वीपी सिंह का अपना न तो कोई कार्यक्रम है न नीति, जिससे कि जनता में उनका कोई असर बढ़े। उनका एकमात्र काम कांग्रेस व खासकर राजीव गांधी की आलोचना करना है। इससे मिली लोकप्रियता चंदरोजा है।

सिंह: मैं पंडितजी व इंदिराजी के साथ काम कर चुका हूं और राजीवजी के साथ काम कर रहा हूं। मेरा वर्तमान कार्यानुभव थोड़े दिनों का ही है। जितने लोग हैं (मंत्रिमंडल में) उनमें से अधिकांश मेरे सामने ही राजनीति में आये हैं। नयी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूं और कुछ दिनों बाद ही मैं उसके बारे में सही राय बना सकता हूं। यह अंतर जरूर है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी हम नयी तकनीक का लाभ उठाकर देश को प्रगति की ओर ले जायें।

माया: पिछले दो दशकों में कांग्रेस ने अनेक चोले बदले हैं। वर्षों से सांगठनिक चुनाव नहीं हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी अलोकतांत्रिक पार्टी का भविष्य क्या होगा?

सिंह: यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी राजनीति और पार्टी को पश्चिमी मापदंड से नापते हैं। हमारी संस्कृति में सबको मिलाकर चलने की परंपरा रही है, जिसे कहते हैं आम सहमति। हम सदैव शक्ति के पूजक होते हुए भी, शक्ति के इस्तेमाल के खिलाफ रहे हैं। हमारा तरीका हमेशा मेलजोल का रहा है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी इन सबकी मध्यममार्गी और समदर्शी नीति रही है। हमारे यहां कभी 'वोटिंग' या मतों की संख्या का प्रचलन नहीं रहा है। मात्र चुनाव ही लोकतंत्र या जनराज्य का चिह्न नहीं है। चुनाव में मतों की संख्या अधिक हो, तो उसे भी लोकतंत्र की एकमात्र निशानी नहीं कहा जा सकता है। अल्पमतों से शासन करने को लोकतंत्र माना जाये या सानुपातिक प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र माना जाये, ऐसे अनेक प्रश्न हैं। हमें ऐसे विचारों में नहीं फंसना है। हमें अपनी परंपरा देखनी है। शुरू से कांग्रेस में मेलजोल और यदाकदा संघर्ष का रूप देखने को मिलता है। बहुत से लोग आये और कुछ पार्टी छोड़कर चले गये और पार्टियां बनायीं। जनसंघ और अब भाजपा को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जिसके नेता कांग्रेस में न रहे हों। कम्युनिस्ट पार्टी तक के अनेक नेता कांग्रेस में रह चुके हैं। इसलिए चुनाव न होने मात्र से पार्टी को अलोकतांत्रिक कहना ठीक नहीं है। यद्यपि चुनाव हों, तो अच्छा है। इससे लोगों के मन का गुबार निकलता है। वस्तुत: चुनाव हमेशा होते रहना चाहिए। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, जिसमें कार्यकर्ताओं के आधार पर विधिवत चुनाव होते हों। मात्र चुनाव न होने से कांग्रेस कमजोर होगी, यह कहना सही नहीं है। पार्टी जब नीतियों, कार्यक्रमों और जनता से अलग होगी, तब उसमें कमजोरी आयेगी।

माया: कांग्रेस के विषय में कहावत है कि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, किंतु संगठन नहीं है।

सिंह: कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह कार्यकर्ता प्रधान पार्टी नहीं है, यह सही है। किंतु इस अर्थ में कांग्रेस को संगठन की आवश्यकता नहीं है। पार्टी मिलजुलकर समान रूप से कार्य करती आयी है। भले ही लोग पार्टी में हों या सरकार में। आज इन सब में दरारें आ रही हैं। लोग पार्टी और सरकार के बीच दीवार खड़ी करने में लगे हैं। यह सही नहीं है। कांग्रेस का इस देश में उज्ज्वल भविष्य है। जो नये तरीके अपनाये जाते हैं, उनसे कुछ-न-कुछ शिकायत लोगों को रहती है। हमें कांग्रेस के नये और पारंपरिक दोनों रूपों का ध्यान रखना चाहिए। सब को साथ लेकर चलने से ही कांग्रेस इतनी सुदीर्घजीवी हो सरकार चला रही है। पार्टी यदि इस मार्ग से हट जायेगी, तो यह घातक होगा।

माया: कांग्रेस पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं पूर्व राजा-महाराजाओं की पार्टी बन गयी है। कालाकांकर

के राजा के रूप में आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सिंह: कालाकांकर के राजा तो सदैव आज़ादी की लड़ाई लडने वालों के साथ रहे हैं। मैं भी उस संघर्ष का एक सेनानी रहा हूं। मैं नहीं मानता कि बड़ी संख्या में राजा-महाराजा कांग्रेस में शामिल हैं। उनका कांग्रेस के बाहर रहना देश और स्वयं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। वह यदि अपनी गलती मानकर कांग्रेस में आयें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कारण कांग्रेस में हर वर्ग के लोग हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को अपनी बपौती समझ रखी है, उन्हें यह भय अवश्य हो सकता है कि नये लोगों के आगमन से उनके दबदबे पर चोट पहुंच सकती है। कांग्रेस में खतरा आयेगा, तो राजा-महाराजाओं से नहीं, पैसे से। इससे हमें खबरदार रहना चाहिए।

माया: राज्यसभा में हुई हाल की घटना, जिसके कारण स्वयं अध्यक्ष ने इस्तीफा देने की सोची, क्या आपके विचार से संसद और लोकतंत्र की तौहीन नहीं है?

सिंह: राज्यसभा एवं लोकसभा तथा उनके अध्यक्षों की अपनी गरिमा है। उसे बनाए रखने का दायित्व सबका है। ऐसे माहौल में ही संसद नियमित और सुचारु रूप से चल सकती है। बीच-बीच में कभी लोग आवेग-आवेश में कुछ कह जाते हैं। अध्यक्ष को इससे कभी-कभी बुरा लगता है। ऐसी स्थिति न आये, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।

माया: आप बहुत दिनों तक संसद सदस्य रहे हैं। ऐसी घटना पहले भी कभी हुई है?

सिंह: घटनाएं तो बीच-बीच में होती रही हैं, कभी उन्हें उछाला जाता रहा है, कभी नहीं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। इससे अधिक अप्रिय बात और क्या हो सकती है?

माया: हाल के मंत्रिमंडल फेरबदल में हिंदीभाषी क्षेत्र को अतिरिक्त महत्व दिया गया है। १३ में से ११ मंत्री वहीं से लिये गये हैं। जिसके विषय में दो बातें कही जा रही हैं—एक तो यह है कि यह मध्यावधि चुनाव का संकेत है। दूसरे यह कि प्रधानमंत्री समझ गये हैं कि अगली जंग इसी क्षेत्र में होगी। इसलिए वह वहां अपने किले मजबूत करने में लगे हैं।

सिंह: कांग्रेस सांसदों की संख्या भी हिंदीभाषी क्षेत्रों में अधिक है। इसलिए जाहिर है कि अधिकतर मंत्री वहीं के बने हैं। किंतु मैं नहीं समझता कि शेष प्रदेशों की अवहेलना हुई है। हर क्षेत्र के लोग मंत्रिमंडल में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र से नहीं चुने जा सके। उन्हें अन्य क्षेत्रों से चुनकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यसभा से चुनकर आने वाले लोगों को भी मंत्रिमंडल में लिया जायेगा। इसलिए किसी फेरबदल में ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।

विपक्ष यहां
कभी नीति के आधार पर
नहीं रहा है। नीति और विचारधारा
कांग्रेस की रही है और कम्युनिस्टों की।
बाकी दल कांग्रेस से किसी-न-किसी
प्रकार जुड़े रहे हैं और उनकी कोई
अपनी विचारधारा नहीं
रही है।

माया: उ०प्र० की वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है और वीपी सिंह का प्रभाव भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या इससे आपको वहां पार्टी के लिए कोई खतरा नजर नहीं आता है?

सिंह: मुझे न तो उ०प्र० में और न किसी अन्य राज्य में ऐसा खतरा नजर आता है। कांग्रेस अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों में यदि असफल रही, तो उसका लाभ वीपी सिंह तथा अन्य विपक्षी दलों को होगा। कांग्रेस को वस्तुत: खतरा किसी व्यक्ति से नहीं, अपने आप से है। अर्थात अपनी स्वीकृत नीतियों तथा कार्यक्रमों से हट जाने से।

माया: क्या नये बजट से किसानों को सचमुच लाभ होगा? जबकि जानकार लोगों का कथन है कि बजट के पहले ही जरूरी जिंसों की मूल्यवृद्धि से हर वर्ग को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे।

सिंह: जनता बेचारी तो हमेशा ही लोहे के चने चबाती रही है—हम लोग भी तो जनता ही हैं, अलग नहीं। हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विकसित देशों में भी यही हालत है। पहले वे बड़े-बड़े मकानों में रहते थे, अब कबूतरखानों में रहते हैं। उनकी संपन्नता पर भी लगाम लगी है। आर्थिक कठिनाइयां हर जगह के साथ-साथ भारत में भी बढ़ रही हैं। मैं यह नहीं मानता कि बजट से किसी विशेष वर्ग को दूसरे वर्ग की कीमत पर लाभ पहुंचाया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस प्रकार बहुसंख्य जनता को लाभ पहुचाना स्वाभाविक है। हमें तो किसानों को और लाभ पहुंचाना चाहिए।

माया: कांग्रेस कंप्यूटर से किसानों की ओर झुक रही है, ऐसा गत छह महीने से उजागर है। क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि उसे यह अहसास हो गया है कि असली वोट बैंक किसान ही हैं?

सिंह: कांग्रेस ने सदा ही किसानों का खयाल रखा है और उनके हित के लिए अनेक कदम उठाये हैं। कांग्रेस का किसानो से संबंध कोई नया नहीं है।

माया: क्या जैल सिंह कांग्रेस को अपने जाल में फंसाने में सफल हो गये और जो काम वह राष्ट्रपति रहते हुए नहीं कर सके, उसे अब कर सकेंगे।

सिंह: मैं समझा नहीं कि आपका क्या आशय है?

माया: जैल सिंह ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें दुबारा खड़ा करने के लिए कांग्रेस वालों ने ही ३०-४० करोड़ रुपया खर्च करने को कहा था। इसकी जांच कराने की जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, यदि उसमें उनके मंत्रियों के ही नाम निकल आये, तो क्या पार्टी को लेने के देने नहीं पड़ जायेंगे और वह जैल सिंह के जाल में नहीं फंस जायेगी?

सिंह: मैं नहीं मानता कि कांग्रेसजन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रचेंगे। मैं यह भी नहीं मानता कि कांग्रेसजन राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने को कहेंगे, या उन्हें रुपयों का प्रलोभन देंगे। मैं यह भी नहीं सोचता कि ज्ञानीजी ने यह माना होगा कि कोई ३०-४० करोड़ रुपए देगा। शून्य का अविष्कार हमने ही किया था। लगता है इस कथित राशि में कुछ शून्य जोड़ दिये गये हैं। जांच से वे बातें सामने आयेंगी। मैं नहीं समझता कि इससे कोई ऐसी बात निकलेगी, जिससे पार्टी या प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचेगी।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

विश्वास के साथ सिफारिश
हर दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन
दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन,
न प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन
प्रतिदिन दिन प्र
तिदिन, न, दिन

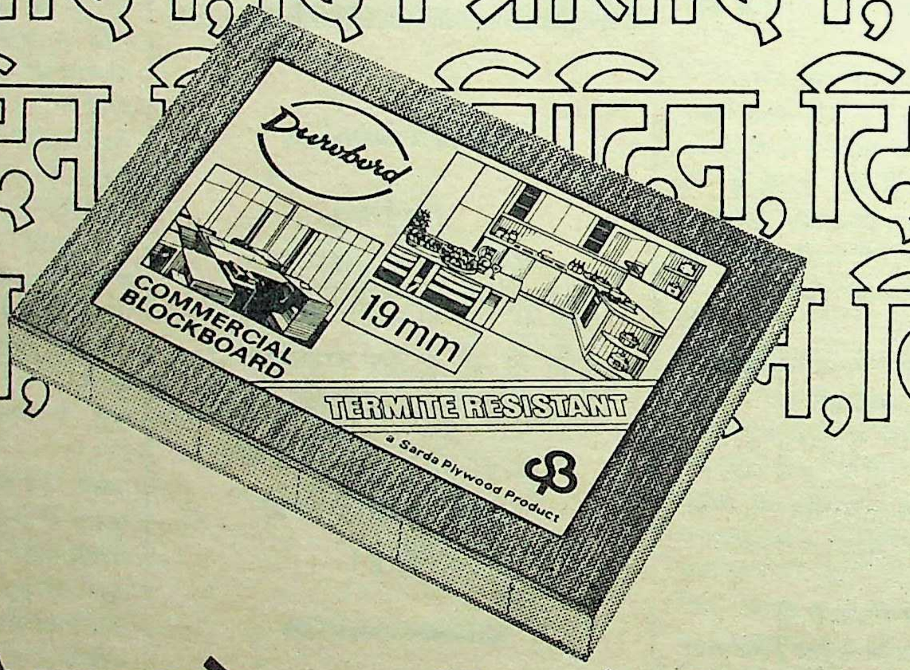
Durobord
COMMERCIAL BLOCKBOARD
19 mm
TERMITE RESISTANT
a Sarda Plywood Product

यह है ड्यूरो – ब्लॉकबोर्ड का हीरो

श्रेष्ठ इंटीरियर डेकोरेटर्स, उत्तम फर्नीचर निर्माता, निपुण
कारीगर, अनुभवी विक्रेता व संतुष्ट उपभोक्ता सभी
सहमत है कि क्वालिटी में ड्यूरोबोर्ड का जवाब नहीं
यही वजह हैं कि ड्यूरोबोर्ड पिछले बीस वर्षों से ब्लॉकबोर्ड
की दुनिया में सरताज है. इसीलिए तो उनकी सिफारिश,
आपके नाम. हर दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन.....

सारदा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
जैपुर (असम)
मुख्य विक्रय कार्यालय [illegible] डी [illegible] रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

DPS/SPI-879

शुजुद्दीन साजिद

रिश्वतखोरो सावधान!

भ्रष्टाचार के सागर को एक बूंद की चुनौती: शुजुद्दीन साजिद

एक स्कूटर सवार, जो पिये हुए लगता था, को सहसा दिल्ली की सड़कों पर स्थान-स्थान पर बने एक चेक पोस्ट पर रोका गया। बीस रुपए के नोट का लेन-देन हुआ। रात के अंधेरे में यह सौदा बेपर्द रहा। स्कूटर सवार के वहां से जाने के बाद पुलिसकर्मी के होठों पर इस कमाई से मुस्कान बिखर गयी। दूसरे ही दिन उस पुलिसकर्मी को एक वरिष्ठ अधिकारी का बुलावा आता है। वहां पहुंचने पर सामने रात वाला स्कूटर सवार बैठा मिला। किंतु पुलिस अधिकारी की वर्दी में।

दिल्ली पुलिस (सतर्कता) के उपायुक्त शुजुद्दीन साजिद अपनी खाकी वर्दी की बिरादरी के बीच आज सर्वाधिक आतंक उत्पन्न करने वालों में एक माने जाते हैं। वेश बदलने में माहिर साजिद का काम पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की जांच करना और कानून-रक्षकों से कानून-भक्षक बनने वालों की धरपकड़ करना है। यह काम सचमुच बड़ा अप्रिय है।

सतर्कता चीफ के खुद बहुरूपिया बन इधर-उधर सूंघने-टटोलने, फंदा डालने से विभाग को भारी लाभ हुआ है। साजिद जनता में पुलिस की खराब छवि के तीन कारण बताते हैं। एक, रिश्वत लेने की आदत, दो अकारण अधिकार, रोब-दाब का प्रदर्शन। तीसरा बेसिरपैर के सवालों में वक्त गंवाना।

साजिद अपनी तीसरी बात का खुलासा करते हुए बताते हैं, "मैं एक रात अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था। मैं वर्दी में नहीं था, इसलिए पुलिस चेक पोस्ट पर मुझे रोका गया। पुलिसकर्मी ने करीब आधे घंटे मुझ से पूछतांछ की। मैं कहां रहता हूं? क्या काम करता हूं? क्या मैंने शराब पी रखी है? मेरे कितने बच्चे हैं? वे कहां पढ़ते हैं? वह अपनी बोरियत मिटाने और वक्त काटने के लिए मेरा समय बरबाद कर रहा था।" ऐसे मामले में फंसे किसी सामान्य निरीह व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है, यह आसानी से समझा जा सकता है।

सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज होते ही एक जांच अधिकारी को ३ या ७ दिनों में जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा जाता है। साजिद का दावा है कि किसी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाता, बशर्ते वह निराधार न हो। "यदि लोग हमें गलती करने वाले पुलिसकर्मी का नाम बताते हैं, तो शिकायत को अनदेखा करने का सवाल ही नहीं उठता," वह जोर देकर कहते हैं।

इस मुद्दे का खुलासा करते वह बोले, "एक बार मैं एक ट्रक चालक के रूप में एक पुलिस थाने गया और ड्यूटी अफसर को बताया कि मुझे एक थैला मिला है, जिसमें १५ हजार रुपए हैं। पर समस्या यह है कि गश्ती पुलिस के एक सिपाही ने मुझे थैला उठाते देख लिया है। अगर आप उसे 'साध' लें, तो अपना 'हिस्सा' पा सकते हैं। लालची ड्यूटी अफसर ने झट ५० प्रतिशत की फरमाइश की। मैंने अपना परिचयपत्र दिखाया, तो उसके होश गुम हो गये। बहरहाल बाद में उसे दंडित किया गया।"

१९८७ में सतर्कता विभाग ने २७ कुसूरवार पुलिसकर्मियों को दंडित किया। यह कार्रवाई डांट-फटकार से लेकर गंभीर मामलों में पदावनति से निलंबन तक होती है। साजिद के अधीन कार्यरत १७ जांच अधिकारी पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने, जनता से दुर्व्यवहार करने और पैसे ऐंठने के मामलों की जांच-पड़ताल में व्यस्त रहते हैं।

साथी-सहयोगियों के अपराध के मामलों की देखरेख पुलिसजनों द्वारा करने में कुछ खामियां भी हैं। इनमें से एक हैं, उनके अपराधों को अनदेखा करने का मोह। मगर इससे होने वाले इस लाभ से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं कि केवल पुलिसकर्मी ही इस धंधे के तमाम गुरों को समझ सकता है।

साजिद बहरहाल ईमानदार पुलिसकर्मियों की प्रशंसा करने में भी कोताही नहीं करते। "पुलिस विभाग में सारे बुरे लोग भरे हैं, ऐसी बात नहीं है", वह कहते हैं। छद्मवेश की अपनी एक मुहिम में उन्होंने एक ड्यूटी अफसर को १५०० रुपए की रिश्वत की पेशकश कर अपने एक 'दुश्मन' के खिलाफ झूठा मामला दायर करने को पटा लिया। किंतु यही हथकंडा जब उन्होंने दूसरे पुलिस थाने पर आजमाया, तो ड्यूटी अफसर ने ऐसी गलत हरकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी।

"इस तरह एक ड्यूटी अफसर को जहां दंडित किया गया, वहीं दूसरे को ईमानदारी के लिए पुरस्कृत," श्री साजिद की टिप्पणी थी।

पुलिस पर पुलिस तैनात करने के लिए सतर्कता विभाग का नेतृत्व पहले एक इंसपेक्टर के हाथ में था। अब उसकी देखरेख का भार पुलिस उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी पर है।" "हम यहां अपने आदमियों के दोषों की जांच-पड़ताल के लिए तैनात किये गये हैं। कोई व्यक्ति टेलीफोन नं०—३३१ व ९८८६ पर हमसे संपर्क कर सकता है या पुलिस मुख्यालय की छठी मंजिल पर हमसे भेंट कर सकता है।" साजिद ने जानकारी दी।

सतर्कता के एक गुप्त कार्रवाई होने के बावजूद जनता को गलती करने वाले सिपाहियों की गतिविधियों और उनके खिलाफ की गयी कार्रवाइयों की जानकारी होनी चाहिए। यह तब और जरूरी हो जाता है, जबकि यह पुलिस बल के भले के लिए हो। और पुलिस को-सही या गलत-शाबासी और वाहवाही कम आरोप, निंदा और आलोचना का निशाना अधिक बनना पड़ता है।

—अनिल शर्मा

कितने पास, कितने दूर : चंद्रशेखर और हेगड़े

लोकदल-अ : जपा का विलय

बगावत को दावत

लोकदल-अ का जनता पार्टी में विलय तो हो गया, लेकिन अजीत सिंह को जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने के विरुद्ध जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो तूफान खड़ा किया है, क्या उससे जनता पार्टी में एक बार फिर दरार पड़ जायेगी ? जनता पार्टी की पांच सदस्यीय समिति जनता पार्टी में लोकदल-ब के विलय के लिये प्रयत्नशील थी, लेकिन अचानक उसमें लोकदल-अ का विलय कैसे हो गया ? इस विलय का जनमोर्चा और विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ?

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर रोड पर स्थित जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी महासचिव यशवंत सिन्हा अपनी पार्टी और लोकदल-अ के विलय के बाद बधाई लेने की जगह सुबह से रात तक पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं तथा कांग्रेस-इ सहित अन्य विपक्षी नेताओं और संवाददाताओं को सफाई देने में जुटे रहे। दूसरी ओर १२, तुगलक रोड स्थित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कोठी में विराजमान उनके पुत्र अजीत सिंह के इर्द-गिर्द मंडरानेवाले सुपरिचित चेहरों का संशय भी छिपाये नहीं छिप रहा था। जिस विलय को दो दलों ने अनेक आशाओं और विश्वासों के साथ पाला-पोसा था, एकाएक वह जन्म के साथ ही विवादों के भंवर जाल में घिर गया था। विलय के स्वागत के स्थान पर प्रश्नचिह्न केवल जनता पार्टी के बहुसंख्यक मुखर नेता ही नहीं लगा रहे थे, भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार 'मीडिया' भी इस अभियान में जोर-शोर से शामिल था। समां तो ऐसा बांधा गया, मानो अजीत सिंह ने लोकदल-अ का झंडा, डंडा, नाम और अस्तित्व मिटा कर घर फूंक तमाशा देखने की लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिया है, तो चंद्रशेखर ने अजीत सिंह को तत्काल कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वंशवाद को बढ़ावा दिया है और उन मूल्यों को मटियामेट कर दिया है, जिनके लिए जनता पार्टी के नेता वर्षों से संघर्षरत रहे हैं।

विपक्षी एकता के प्रयास पिछले एक वर्ष से, विशेषकर राजीव सरकार के विरुद्ध बोफोर्स तोपों की बौछार के बाद से शुरू हो चले थे। पूर्व वित्त और रक्षामंत्री तथा राजीव कैबिनेट में नंबर दो रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा कांग्रेस-इ से निकलकर आक्रामक मुद्रा अपनाने के बाद इसकी गति और तीव्र हुई थी तथा जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स व जनमोर्चा के संयुक्त मोर्चे के गठन के रूप में इसकी भूमिका भी बन गयी थी। लेकिन इस संयुक्त मोर्चे के गठन के पूर्व जनता पार्टी के साथ लोकदल-अ की नहीं, बल्कि लोकदल-ब के विलय की चर्चा जोरों पर थी और बाद में लोकदल-ब को इस चार पक्षीय मोर्चे में जोड़ने के लिए स्वयं चन्द्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जहां सक्रिय थे, वहीं विलय के लिए जनता पार्टी की ५ सदस्यीय समिति, (जिसमें बीजू पटनायक, मधु दंडवते, जार्ज फर्नांडीस, रामकृष्ण हेगड़े और इंदूभाई पटेल शामिल थे) भी प्रयत्नशील थी। अत: लोकदल-अ से विलय की सूचना ने विपक्ष, विशेषकर स्वयं जनता पार्टी के नेताओं को हतप्रभ कर दिया।

विरोध के मुद्दे : जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, दो परस्पर विरोधी मत प्रस्तुत किये जा रहे हैं। असंतुष्टों की वाणी मुखर करते हुए जार्ज फर्नांडीस कहते हैं, "पार्टी अध्यक्ष द्वारा सही दिशा में उठाया गया यह एक गलत कदम है।" उनका संकेत संयुक्त पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की ओर है। अन्य असंतुष्ट नेताओं, जिनमें बीजू पटनायक प्रमुख हैं, का कहना है कि बिना पार्टी में व्यापक विचार-विमर्श किये पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने मनमाने तरीके से विलय का यह कदम उठाया है (देखिए साक्षात्कार)। इन लोगों के रोष का इससे भी अधिक कारण है, अजीत सिंह का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना।

असंतुष्टों का दावा है कि विलय संबंधी निर्णय का अधिकार पार्टी संसदीय बोर्ड को भी नहीं है, अध्यक्ष की तो बात ही क्या ? यह महत्वपूर्ण फैसला केवल पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ही कर सकती है।

क्या ताकत बढ़ी ? : सुब्रह्मण्यम स्वामी, अजीत सिंह'

इन नेताओं का कहना है कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की गत ५ मार्च की बैठक ने भी अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसे विलय संबंधी फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल पार्टी की राष्ट्रीय परिषद को ही प्राप्त है। यद्यपि राष्ट्रीय परिषद अपने कुछ अधिकारों को अध्यक्ष को सौंप सकती है, किंतु पार्टी के संविधान के अनुसार विलय संबंधी फैसला मात्र उसी के द्वारा लेना चाहिए। वैसे भी जनता पार्टी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है और यदि कोई प्रावधान होता भी तो अजीत सिंह' की नियुक्ति किस योग्यता के आधार पर हुई, यह प्रश्न भी असंतुष्टों ने उठाया है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस कदम को उठाकर कांग्रेस-इ के वंशवाद को ही अपनाया गया है, जिसके तहत व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में उसके जनाधार, उपलब्धियों और योग्यताओं को नहीं, उसके जन्म और वंश को अधिक महत्व दिया जाता है।

विद्रोहियों का आरोप है कि ऐसा करके विपक्षी एकता का द्वार खोलने की जगह उसे बंद कर दिया गया है। इस संबंध में लोकदल-ब को दरकिनार कर दिया गया है जिसे एक राज्य हरियाणा के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता ही नहीं मिली, वहां उसका मुख्यमंत्री भी है और कुछ अन्य हिंदी भाषी राज्यों में उसका अच्छा-खासा असर है। लोकदल-ब के जपा में विलय संबंधी बातचीत पर अमल ऐन करीब था और पांच-सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही थी कि उसी दौरान सहसा लोकदल-अ के विलय की घोषणा करके इस समूची प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया गया।

पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर सहित विलय समर्थकों का खेमा इन आरोपों से अत्यंत खिन्न है। महासचिव यशवंत सिन्हा ने 'माया' से बातचीत के दौरान कहा, "हमारी पार्टी इतनी अधिक लोकतांत्रिक है कि इसके मंच पर विपरीत स्वरों का सुनाई देना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी मध्यार्गी पार्टी के अध्यक्ष के सिर पर कांटों का ताज होता है। उसका काम पांच दिशाओं में भागनेवाले चार घोड़ों को संभालना होता है।"

समर्थकों के तर्क : जहां तक संविधान की बात है, उसके विषय में विलय समर्थकों का कहना है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष का उसमें यदि प्रावधान नहीं है, तो विलय संबंधी किसी निश्चित बात का भी उल्लेख नहीं है। यह कहना भी सरासर गलत है कि यह फैसला एकाएक बिना विचार-विमर्श के और मनमाने ढंग से किया गया। स्वयं संसदीय बोर्ड ने जब अध्यक्ष को इसे अंतिम रूप देने का अधिकार सौंपा, उसके बाद ही यह फैसला लिया और लागू किया गया।

समर्थकों के अनुसार जनता पार्टी के पिछले कई महीनों का इतिहास देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि पार्टी लोकदल-ब को अधिक महत्व देती रही है। लेकिन लोकदल-ब को अपने से जोड़ने के उसके सभी प्रयास विफल रहे हैं। एक वरिष्ठ जनता नेता का कहना है, "विलय तो दूर, वे लोग तो हमारे चार पक्षीय मोर्चे में भी शामिल नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हम 'महामहिम' देवीलाल की कब तक बाट जोहते।"

जानकार सूत्रों के अनुसार, विलय संबंधी लोकदल-अ अध्यक्ष अजीत सिंह का पत्र जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर को गत जुलाई में ही प्राप्त हो गया था। किंतु, उस समय लोकदल-ब के साथ विलय संबंधी चर्चा जोर पकड़ने से उस पत्र पर कार्रवाई स्थगित रखी गयी, क्योंकि लोकदल-अ से [illegible] जैसा आचरण करने वाले लोकदल-ब को यदि उक्त पत्र की भनक मिल जाती, तो वह भड़क उठती।

इन सूत्रों का यह भी कहना है कि अजीत सिंह को मात्र अल्पकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कोई भारी गुनाह नहीं किया गया है। पार्टी अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव आगामी अप्रैल में होनेवाले चुनाव में करने की ही बात कही है। उस चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। अजीत सिंह ने भी इसी बात पर बल दिया है (देखें साक्षात्कार)। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंखें मूंदकर यदि कोई अजीत सिंह को पार्टी पर थोपने का आरोप लगाता है, तो यह सरासर गलत है। इसी प्रकार विलय संबंधी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, जार्ज फर्नांडीस आदि नेता मौजूद थे। इनमें से मात्र बीजू पटनायक ने दबे स्वर में अपना असंतोष व्यक्त किया था। शेष लोगों ने मौन रहकर विलय का समर्थन ही किया था।

जनता पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र का कहना है, "अजीत सिंह बिना शर्त विलय के लिए तैयार हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी ओर से सद्भावना की यह सामान्य अभिव्यक्ति यदि किसी को अप्रिय प्रतीत होती है, तो यह सही नहीं है। लोकदल-अ से आये लोगों से चर्चा चलने पर उन्होंने कहा कि असंतुष्टों का विरोध मात्र उसी प्रकार लगता है जैसे निबंध में व्याकरण संबंधी दोष निकालकर उसके गुणों को भुला दिया जाये। यह तो निहित स्वार्थों द्वारा भड़कायी गयी आग है।"

चार पक्षीय संयुक्त मोर्चे के एक नेता ने 'माया' को बताया कि लोकदल-अ जपा विलय की कुछ भनक उन्हें बंगलोर में जनता शासन के पांच वर्ष पूरे होने के समारोह के दौरान विभिन्न नेताओं

साक्षात्कार/अजीत सिंह

‘विलय मुद्दों की बुनियाद पर हुआ है’

लोकदल-अ का जनता पार्टी में विलय तो हो गया, लेकिन स्वयं जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसका घोर विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या इस विलय के साथ ही जनता पार्टी में नये बिखराव की भूमिका बनने लगी है? क्या अजीत सिंह को इसके लिए जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने का लालच दिया गया? ऐसे ही अनेक सवालों पर 'माया' ने जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह से लंबी बातचीत की है। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

माया: लोकदल-अ और जनता पार्टी का विलय किस आधार पर हुआ?

अजीत सिंह: आधार यही है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हों। चंद्रशेखरजी, वीपी सिंहजी और हम जहां भी गये हैं, जनता की यही मांग रही है कि कांग्रेस के खिलाफ सभी दल एक हों। लगभग सभी दल और नेता यही चाहते हैं। इस दिशा में हमने कदम उठाया है। आधार यही है कि जनता पार्टी और लोकदल का एक ही चुनाव-घोषणा पत्र हो, जिसका आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना है।

माया: कहा जा रहा है कि लोकदल ने यह विलय बिना शर्त किया है?

सिंह: हमने ही नहीं, जनता पार्टी ने भी बिना शर्त विलय किया है। नाम और झंडा भी वही है जनता पार्टी का जो चौधरी चरण सिंह द्वारा दिया गया था।

माया: यदि विलय बिना शर्त हुआ है, तो आपको कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, जबकि जनता पार्टी के संविधान में ऐसे किसी पद की व्यवस्था नहीं, न ही कोई आपातकालीन परिस्थिति थी।

सिंह: ऐसी भी तो कोई शर्त नहीं थी कि अजीत सिंह को पद न दिया जाये। संविधान में तो विलय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार तो विलय भी नहीं होना चाहिए। कोई नयी चीज तभी बनेगी, जबकि उसमें नये और पुराने का योग हो। लकीर का फकीर बनने से यह संभव नहीं।

माया: विलय की पहल कब, क्यों और कैसे हुई?

सिंह: जैसाकि मैंने कहा, हम लोग ८ महीने से साथ-साथ रैलियां, सभाएं आदि कर रहे हैं। इससे पारस्परिक संपर्क, सहयोग, विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी बात, हम लोगों के सामने जनता का 'मूड' भी उजागर हुआ। लोगों की तीव्र आकांक्षा है कि कांग्रेस की भ्रष्ट, विफल और जनविरोधी सरकार को अपदस्थ करने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक हो जाना चाहिए। यह जन-दबाव चंद्रशेखरजी ने भी अनुभव किया और हमने भी। इससे बने संपर्क और समझदारी ने हमें विलय के लिए प्रेरित किया। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हमने पाया कि विभिन्न श्रमजीवी सामाजिक शक्तियां एकजुट हो जायें, तो कांग्रेस को पैर रखने की जगह नहीं मिल पायेगी।

माया: क्या यह विलय उत्तर प्रदेश और बिहार में मात्र शक्ति संवर्धन के लिए किया गया है?

सिंह: नहीं। स्थिति यह है कि लोकदल-अ, खासकर उत्तर में प्रभावशाली है और लोकदल-ब का भी यही क्षेत्र है और जनता पार्टी का अधिकतर प्रभाव दक्षिण में है। दक्षिण में हमारी तथा उत्तर में जनता पार्टी की जो शक्ति है, वह गिनी-चुनी है। इसलिए इस विलय के बाद नये दल की शक्ति बहुत बढ़ जायेगी। ऐसा हमारा विश्वास है।

माया: विलय में पहल आपकी ओर से हुई है या जनता पार्टी की ओर से?

सिंह: जैसाकि मैंने कहा, हम गत ७-८ महीनों से मिलते-जुलते रहे हैं। मैंने श्री चंद्रशेखरजी को पत्र लिखा, उन्होंने जवाब दिया। हमारे बीच ३-४ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। कोई शर्त नहीं रखी गयी—न उनकी ओर से, न हमारी ओर से। यह बीजू पटनायक जो आज अलग स्वर में बात कर रहे हैं, वह जनता पार्टी की उस समिति के एक सदस्य थे जो लोकदल-ब के विलय के लिए पिछले ६ महीनों से बातचीत चला रही थी और जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वह कभी नाम, तो कभी झंडे को लेकर उलझे रहे। इतने लंबे अरसे के बाद भी वह विलय के लिए समझौता क्यों नहीं कर पाये। मैं तो कहीं बीच में नहीं था।

माया: गत वर्ष जनता पार्टी का लोकदल-ब से विलय का प्रयास जारी था जो विफल रहा। क्या उस नाकामी का नतीजा लोकदल-अ का जनता पार्टी में विलय का कारण बना?

सिंह: ऐसी बात नहीं है। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। लोग समझ गये हैं और बिहार में लोकदल-अ का अच्छा-खासा असर है। और जैसाकि हमने कहा था कि हम लोकदल-ब के खिलाफ नहीं हैं, उनके विलय का हम स्वागत करते हैं, किंतु बीजू पटनायक ने ही इसका विरोध किया था।

माया: विलय का यह फैसला दोनों पार्टियों का था या उनके चंद नेताओं का?

सिंह: हमने अपनी पार्टी में इस विषय में विस्तार से बात की थी। चंद्रशेखरजी ने भी बताया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लगभग सभी नेताओं से इस विषय में बात की थी। संभव है, वह बीजू पटनाय जैसे एकाध नेताओं से बात न कर पाये हों, क्यों वह लगभग ३ महीनों से अपने राज्य के सुदूर दौ में व्यस्त थे। इसके अलावा श्री चंद्रशेखर को उन पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी व संसदीय बोर्ड विलय का अधिकार दे चुकी है। हमारी पार्टी ने यही रवैया अख्तियार किया था।

माया: यदि दोनों पार्टियों का फैसला था, तो सह इतना अधिक विरोध क्यों उठ खड़ा हुआ?

सिंह: कोई भी बडी चीज होती है, तो थोड़ी ब उथल-पुथल होती ही है। जनता पार्टी के पिछले चुनाव में इससे बड़े झगड़े हुए थे, इसलिए यह मु ज्यादा गंभीर नहीं है। दो दलों के विलय की प्रक्रिय में कुछ निहित स्वार्थों का टकराव अस्वाभावि नहीं है। कांग्रेसवाले भी लगातार विपक्षी एकता के खिलाफ तिकड़मों में लगे रहते हैं।

माया: आपके विचार से विरोध व्यक्तिगत है या सैद्धांतिक?

सिंह: ऐसे मामलों में सैद्धांतिक विरोध के नाम प प्राय: व्यक्तिगत विरोध मुखरित होते हैं। वैसे, य विरोध सैद्धांतिक तो कतई नहीं, क्योंकि विलय सभी पक्षधर हैं। मैं इसे व्यक्तिगत विरोध भी न कहूंगा, क्योंकि कोई मेरे खिलाफ नहीं है। मेरे सब बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ लोगों का मत है कि विल में थोड़ा और समय लगता, विचार-विमर्श होता, अच्छा था। किंतु मैं समझता हूं कि इससे बातें उलझती हैं, सुलझती नहीं।

माया: जिस समय विलय का निर्णय लिया गया, उ समय विरोध की संभावना आपको नजर आयी थी

सिंह: हमने उस समय अधिक ध्यान इसी पर दि था कि विपक्ष को कितनी शक्ति मिलती है। विरो के विषय में नहीं सोचा था। वैसे, सब इससे सहम हैं।

माया: फिर एकाएक इतना विरोध क्यों?

सिंह: बीजू पटनायक जैसे इक्के-दुक्के को छोड़क किसी ने विरोध नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस २८ विरोधियों के जो नाम गिनाये हैं, उस पर भ कौन एतबार करेगा। मैं तो इसे उसकी एक शर्मना करतूत कहूंगा। क्या एक दिन में विरोधियों टेलीग्राम आ सकते हैं? यह तो कुछ लोग विरो कर रहे हैं जो विपक्ष की एकता का शोर मचाते और एकता होने पर विरोध करते हैं।

माया: विपक्षी एकता को इस विलय से कितना ला पहुंचेगा?

सिंह: जैसाकि मैंने कहा उत्तर प्रदेश, बिहार में सब बड़ी शक्ति जनता व लोकदल-अ है। वीपी सिं चंद्रशेखर और हम जहां भी गये हैं, अपार जनस ने यही मांग की है कि हम लोग एक हो जायें। ह लोगों ने ऐसा ही किया। वीपी सिंह का भी ह भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।

माया: आप दोनों का तो विलय हो गया। विपक्ष की एकता का क्या हश्र होगा?

सिंह: आप साफ नाम क्यों नहीं लेतीं कि लोकदल कब मिलेगा?

ाया : लोकदल-ब ही नहीं, जनमोर्चा आदि भी तो ?

सह : जनमोर्चा ने तो अभी अपने राजनीतिक वरूप की घोषणा नहीं की है। जहां तक कांग्रेस-स का प्रश्न है, वह कभी भी आ जाये, तो इतने बड़े समीकरण में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लोकदल-ब के विलय का तो मैं सदैव से स्वागत करता रहा हूं। यदि मुझसे ही चिढ़ है, तो वह विभिन्न पार्टियों के बने संयुक्त मोर्चे में क्यों नहीं आये जो १४ सूत्री जनमांगों को लेकर आंदोलन चला रहा था। यह तो आप लोकदल-ब से पूछिए कि वह कांग्रेस-इ से लड़ना चाहती है या अजीत सिह से। उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हमें भाजपा से बात नहीं करनी और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वह भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। वह आपस में विपक्षी एकता के बारे में र्वसम्मत फैसला लें, कदम उठायें, तो हमें खुशी होगी।

ाया : ऐसे गठबंधनों को अतीत में विफलता का मुंह खना पड़ा। इससे बचने के लिए आपने क्या उपाय ोचा है ?

सह : ऐसे गठबंधन अतीत में कभी नहीं हुए। पहले ए गठबंधनों में महीनों चर्चा चली है। नाम, झंडा, ुनाव चिह्न और पदों को लेकर विवाद होते रहे हैं। स बार विलय हुआ है, इन तमाम बातों को भूलक वपक्षी एकता की आवश्यकता को मद्देनजर रखते ए फौरी और बिना शर्त फैसला लिया गया।

ाया : इसकी महत्ता क्या है ? क्या चुनाव संभावना ो दृष्टि में रखकर यह विलय आपने किया है ?

सह : हम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, इसलिए ुनाव को तो नजर में रखना ही पड़ेगा। किंतु यह लय मुद्दों की बुनियाद पर हुआ है। दोनों के षणापत्र एक हैं, जिसको स्वयं चौ० चरण सिंह ने ार किया था और वही जनता पार्टी तथा ोकदल के संस्थापक भी थे। इस प्रकार यह विलय द्धांत एवं व्यवहार दोनों दृष्टियों से समुचित है।

ाया : १२ मार्च को राष्ट्रीय संजय मंच का भी लय हुआ है। यह विपक्षी ध्रुवीकरण किश्तों में यों ?

सह : इससे एक माहौल पैदा हुआ। वैसे तो लोग पक्षी एकता के लिए बैठकें करते हैं, बात चलाते हैं र हाथ झाड़कर अलग हो जाते हैं। सूरजकुंड म्मेलन का हश्र सामने है। वह रास्ता अब खतम हो का है। अब यही रास्ता बचा है।

ाया : कैसा रास्ता ?

सह : जो भी आना चाहे, विलय के लिए तैयार हो, ह आ जाये, उसका स्वागत है। यह कहना कि अभी लाह कर लें, इसका कोई नतीजा निकलनेवाला हीं। पिछले २ साल से ऐसा ही हो रहा है। कोई ता ३०-४० लोगों को बुला लेता है, बात होती है, वत होती है और लोग अपने-अपने घर चले जाते

ाया : क्या आपको आशंका है कि आपके विधिवत ध्यक्ष बनाने के मार्ग में रोड़े अटकाये जायेंगे ?

सह : रोड़े अटकाये जायेंगे या मुझे पद नहीं मिलेगा, इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है कि विलय बिना शर्त, बिना किसी मांग के हुआ है और जैसा श्री चंद्रशेखर ने बयान में कहा है कि वह अध्यक्ष पद के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव करेंगे। यदि और लोग भी उक्त पद के उम्मीदवार होंगे, तो उनका स्वागत है।

माया : प्रेस के एक हिस्से में लिखा जा रहा है कि यह विलय विघटनकारी होगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे ?

सिह : कुछ लोग यदि विघटनकारी कामों में विश्वास रखते हैं, तो उनके विषय में मैं क्या कह सकता हूं ?

माया : अपनी पार्टी के विलय के बाद उस स्थिति में क्या आपने वापस आने का कोई मार्ग खुला रखा है ?

सिह : हमने कोई मार्ग खुला नहीं रखा। किंतु हमारा जो 'वोटर' है, वह बना रहेगा।

माया : संयुक्त दल के अध्यक्ष के रूप में आपकी भावी रणनीति क्या होगी ?

सिह : हमारी पहली कोशिश होगी, जितने भी छोटे अथवा बड़े दल हैं, एक साथ आयें। दूसरा, चुनाव में अब अधिक दिन नहीं रह गये हैं, इसलिए हम इसकी रणनीति और योजना तय करें। कांग्रेस-इ के पास तो विशाल साधन और बड़ा संगठन है। हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में यदि हम यह सोचकर बैठे रहें कि पहले हम सब एक हो जायें, तब तैयारी शुरू हो, तो उम्मीदवारों के चुनाव के सवाल पर ही झगड़ा शुरू हो जायेगा। हमें कार्य शुरू करना है, मतदाता सूची तैयार करनी है, उम्मीदवारों का चुनाव करना है।

माया : कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, कांग्रेस-इ को हटाओ और उसका कोई अन्य ठोस कार्यक्रम नहीं है।

सिह : कांग्रेस का तो स्वयं सदा से एक सूत्रीय कार्यक्रम रहा है, सत्ता से येन-केन प्रकारेण चिपके रहो। चाहे इसके लिए 'गरीबी हटाओ' अथवा 'काम करनेवाली सरकार' जैसे नारों का ही सहारा क्यों न लेना पड़े अथवा हिंदू-मुसलमानों के झगड़े कराने पड़े या झूठा बजट तैयार करना पड़े। विपक्ष का सदैव एक वैकल्पिक कार्यक्रम और नीति रही है।

माया : यह भी आरोप है कि कांग्रेस की भांति आप एक विशेष वंश का शासन चला रहे हैं।

सिह : वंश का शासन चलाने का मतलब तो यह है कि मैं अपने बेटे को ला रहा हूं। यदि चौधरी साहब ने चलाया होता, तो इसका मतलब है कि वह मुझे पार्टी में ले आते। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जबकि सचाई यह है कि जवाहर लाल नेहरू ने अपने सामने इंदिरा गांधी को बढ़ाया और इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को। वंशावली का शासन इसे कहते हैं। ये लोग सीधे सत्ता में आते रहे हैं। अपने बलबूते राजनीति नहीं की है। हमने अनेक पद-यात्राएं, सभाएं की हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं, हमारा अपना दल, शक्ति और जनसमर्थन है। इसलिए मुझ पर यह आरोप लगाना तथ्यों को झुठलाना है।

—रं०कु०

के बीच हुई बातचीत से लग गयी थी। किंतु उस समय इस बात पर जोर देते हुए जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर को राय दी गयी थी कि इस प्रकार का कोई भी कदम बिना व्यापक संदर्भों में विचार-विमर्श किये जल्दबाजी में नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही सोच-समझकर और धीमी गति से फैसला लेने को कहा गया था। इतनी बातचीत के बाद भी सहसा लिये गये इस निर्णय ने विपक्षी एकता के संभावित समीकरणों को गड़बड़ा दिया।

संजय विचार मंच से कुछ ही दिनों के फासले में किये गये विलय संबंधी समझौते ने जैसे यह उजागर कर दिया कि विलय की यह प्रक्रिया किस्तो में जारी रहेगी। इस पर तीव्र असंतोष प्रकट करते हुए जपा के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस सहित विलय विरोधियों को भितरघात करने का बैठे-बिठाये सुनहरा मौका हाथ आ गया है।

> जनता पार्टी-लोकदल-अ के विलय की घोषणा से विपक्षी एकता के समीकरणों में भारी उलटफेर होने के आसार नजर आने लगे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि संयुक्त मोर्चे के घटक (जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स व जनमोर्चा) ३० मार्च तक लोकदल-ब की प्रतीक्षा करें। उसके बीच यदि लोकदल-ब उसके साथ आता है, तो इस मोर्चे को एक दल का रूप देने का प्रयास किया जाये। इसका प्रयास जारी था कि जनता पार्टी लोकदल-अ के विलय ने यह सारा समीकरण ही बदल दिया।

जनता पार्टी-लोकदल-अ के विलय की घोषणा से विपक्षी एकता के समीकरणों में भारी उलटफेर होने के आसार नजर आने लगे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिह चाहते थे कि संयुक्त मोर्चे के घटक (जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स व जनमोर्चा) ३० मार्च तक लोकदल-ब की प्रतीक्षा करें। उसके बीच यदि लोकदल-ब उसके साथ आता है, तो इस मोर्चे को एक दल का रूप देने का प्रयास किया जाये। इसका प्रयास जारी था कि जनता पार्टी लोकदल-अ के विलय ने यह सारा समीकरण ही बदल दिया। चर्चा है कि संयुक्त मोर्चा के महत्वपूर्ण घटक जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिह को विलय की यह सूचना मात्र दो घंटे पूर्व सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दी थी।

विलय की इस जल्दबाजी का फौरी असर यह हुआ कि भाजपा-जनमोर्चा एक-दूसरे के करीब आ

गये। जनमोर्चे के अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खां की भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से राज्यसभा की सीटों के तालमेल पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। जनता पार्टी ने भी अनचाहे मुसीबत मोल ले ली है। इससे यदि कांग्रेस-इ के अतिरिक्त कोई दल अत्यधिक प्रसन्न है, तो वह है लोकदल-ब। इस दल के बिहार के एक नेता का कहना है, "हमें इस बात की खुशी है कि बिना परिश्रम के ही समूचे लोकदल पर हमारा अधिकार हो गया है।" लोकदल-ब और भाजपा की एकजुटता के बीच जो थोड़ी बहुत कमी थी, वह भी इसके बाद दूर हो गयी है। राजस्थान और बिहार में उनमें सुदृढ़ तालमेल पैदा हो गया है और उत्तर प्रदेश में जहां उनका नेतृत्व विपरीत ध्रुवों में था, वह भी पहली बार परस्पर एकता के उद्देश्य से एक साथ मिल बैठे हैं।

प्रसन्नता की लहर वामपंथी खेमे में भी भरपूर है, किंतु विभिन्न कारणों से। उसके नेताओं का अनुमान है कि इससे मध्यमार्गीय विपक्षी एकता में बाधा पहुंचेगी और हो सकता है कि एक गुट की जगह अनेक गुट बने रहें। ऐसी हालत में उनकी खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां वामपंथ का अपना आधार नगण्य है। विभिन्न गुटों से तालमेल व चुनावी मोल-तोल करने की ताकत बढ जायेगी।

चंद्रशेखर की मजबूरी : प्रश्न यह है कि विपक्षी एकता के समीकरणों में ज्वार-भांटा पैदा करनेवाला यह कदम जनता पार्टी विशेषकर अध्यक्ष चंद्रशेखर ने क्यों और किन परिस्थितियों में उठाया? इसके बारे में अनेक कारण गिनाये जाते हैं। यह सर्वविदित है कि जनता पार्टी के चुनाव आगामी अप्रैल-मई में होने तय थे। इसके साथ ही यह भी सर्वमान्य है कि पार्टी के जन्म से लेकर आज तक अध्यक्ष का सिंहासन न खाली करनेवाले चंद्रशेखर पर अपनी ही पार्टी के असंख्य नेताओं की आलोचना की बौछार हो रही थी, अतः भावी चुनाव के दौरान चंद्रशेखर के लिए आवश्यक हो गया था कि अपनी छवि बनाये रखने के लिए पद त्याग तो करें, किंतु अपनी शक्ति और प्रभाव पूर्ववत बरकरार रखें। इसका सहजतम रास्ता यही था कि लोकदल-अ का विलय और अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष पद देकर वह अपनी मनोकामना पूरी करें।

चौधरी चरण सिंह के साथ वर्षों काम कर चुके एक नेता ने 'माया' से बातचीत में बताया कि जनता पार्टी—लोकदल विलय की बातचीत १९८४ में ही चली थी और महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचने के पूर्व ही टांय-टांय फिस हो गयी थी। इसका मूल कारण था, जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर का एकाएक वार्ता से पीठ फेर लेना। क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदी भाषी क्षेत्रों के दिग्गज किसान नेता चौधरी चरण सिंह के वर्चस्व के सामने वे स्वयं राजनीतिक रूप में बौने हो जायेंगे। लोकदल-अ की मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई खतरा उन्हें नजर नहीं आता। खासकर राजनीति के दांवपेंचों से अनभिज्ञ अजीत सिंह को चंद्रशेखर अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं।

साक्षात्कार/**बीजू पटनायक**

'वरिष्ठ नेताओं की राय लिये बिना विलय का फैसला लिया गया'

जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र व सहयोगी तथा उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अपने राज्य के बहुर्चचित मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक की ही आंख की किरकिरी नहीं बने हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के लिए भी आज सांसत बन गये हैं। जनता-लोकदल-अ विलय के मुद्दे पर तूफान खड़ा करनेवालों में प्रमुख बीजू पटनायक से 'माया' की बातचीत के अंश :

माया : आप जनता-लोकदल-अ के विलय का विरोध क्यों कर रहे हैं?

बीजू : मैं विलय का विरोधी नहीं हूं। विलय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अन्य साथियों के साथ गत एक वर्ष से समान विचारधारा की पार्टियों के गठबंधन और विलय के लिए प्रयासरत रहा हू। ऐसी स्थिति में विलय का विरोध हम भला कैसे कर सकते हैं? हां, इस विलय के लिए जो प्रक्रिया अपनायी गयी है, उसका हमने विरोध किया है।

माया : कौन सी प्रक्रिया?

बीजू : पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने व्यापक रूप से इस पर विचार-विमर्श किये बिना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय-सलाह जाने बिना जो एकतरफा फैसला लिया है, वह उचित और सर्वमान्य नहीं है।

माया : आम धारणा यही है कि विलय विरोधी चिनगारी आपकी भड़काई हुई है?

बीजू : विरोध का स्वर मेरा अकेला नहीं है। पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ और गंभीर विचारवाले नेताओं—जैसे मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े, जार्ज फर्नांडीस, जयपाल रेड्डी, सुरेंद्र मोहन आदि ने इस संबंध में पार्टी-अध्यक्ष को अपने असंतोष और विरोध से अवगत करा दिया है। यही नहीं सामान्यजनों और पत्र-पत्रिकाओं की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया रही है।

माया : यदि विरोध विलय का नहीं है, तो क्या अजीत सिंह के कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने का है?

बीजू : हां। अजीत सिंह से मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष या विरोध नहीं, किंतु राजनीति में व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का महत्व होता है। अजीत सिंह की स्वर्गीय चौ० चरण सिंह के पुत्र होने के अतिरिक्त और क्या राजनीतिक कमाई है। यह तो एक प्रकार से कांग्रेस-इ में प्रचलित वंशवाद की ही एक भौंड़ी नकल होगी, जिसका हम लोगों ने वर्षों से जबर्दस्त विरोध किया है। यदि हम अजीत सिंह को गद्दीनशीं करते हैं, तो उनमें और राजीव गांधी में क्या फर्क होगा। इसके अतिरिक्त अजीत सिंह के आगे-पीछे ऐसे निहित स्वार्थों का भी जमघट है, जैसे—सुब्रह्मण्यम स्वामी, जिन्हें पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण अनेक जगहों से हटाया जा चुका है। ऐसे लोग अजीत सिंह के राजनीतिक व्यक्तित्व के विकास में बाधक रहेंगे और उन्हें जनता-जनार्दन से दूर रख गुमराह करते रहेंगे।

माया : यदि आप अजीत सिंह के कार्यकारी अध्यक्ष होने के खिलाफ हैं, तो किसे इस पद पर लाना चाहते हैं?

बीजू : मैं स्वयं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लाना चाहता। किंतु, हमारी पार्टी में वरिष्ठ, लोकप्रिय, अनुभवी, कुशल और सर्वमान्य नेताओं की कोई कमी नहीं। पार्टी को सुदृढ़ करने, उसका जनाधार बढ़ाने और समान विचारधारावाली पार्टियों के विलय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर आसीन हो, जिसमें व्यापक राजनीतिक पकड़, सांगठनिक समझदारी और कौशल हो। फिलहाल, अजीत सिंह इस कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते। अनुभव और अभ्यास अवश्य ही उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का समुचित विकास करेगा। तब उनके नाम का समर्थन इक्का-दुक्का लोग नहीं, पार्टी का व्यापक नेतृत्व वर्ग करेगा।

माया : इस समस्या का समाधान क्या पार्टी कर पाने में सफल होगी? कैसे?

बीजू : पार्टी अवश्य ही समस्या को सुलझा सकेगी। मिलजुलकर विचार करने से कोई रास्ता जरूर निकल आयेगा। इस सिलसिले में अनौपचारिक वार्ता के अतिरिक्त हम लोगों ने पार्टी अध्यक्ष से कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।

—रं०क० और त्रि०श्री०

अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा : रामकृष्ण हेगड़े और मेनका गांधी

संयुक्त मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चन्द्रशेखर विपक्षी पार्टियों की एकता तो चाहते हैं, किंतु अपना निर्विवाद प्रभुत्व खोना नहीं चाहते। विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भी जनता पार्टी अध्यक्ष ने कुछ दिनों पूर्व यह शर्त लगा दी थी कि वह पहले वित्त मंत्री के रूप में अपनी गलत नीतियां स्वीकार करें, तभी उन्हें शिरोधार्य किया जायेगा। इसके बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता के चलते चंद्रशेखर अपने भविष्य के प्रति चिंतित-सशंक्ति हो उठे हैं। खतरा उन्हें देवी लाल की शक्ल में भी दिखाई देता है। लोकदल-ब का विलय न होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि देवीलाल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव चंद्रशेखर के गले नहीं उतरा था।

इस विपक्षी नेता के अनुसार विपक्षी एकता के लिए चन्द्रशेखर का एक सूत्री कार्यक्रम यह रहा है कि जनता पार्टी को अन्य दलों के विलय में केन्द्रीय भूमिका प्राप्त हो और वह उसके सर्वोच्च नेता बने रहें और 'मौका' आने पर वह अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को मात दे सकें।

विलय का असर : चन्द्रशेखर ने एक तीर से अनेक शिकार किये हैं। पहला अजीत सिंह को मोहरा बनाकर उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक, मधु दंडवते जैसे जपा अध्यक्ष पद के इच्छुक-अनिच्छुक पार्टी नेताओं के सपनों का महल ढहा दिया है। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावशाली जनमोर्चे से मोल-तोल करने की अपनी शक्ति बढ़ा ली है, क्योंकि विलय के पश्चात हिंदी भाषी क्षेत्र के हृदय भाग उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सबसे मजबूत स्थिति हो गयी है। (देखिए बाक्स) अटकल लगाने वाले यह भी कह रहे हैं कि राजनीति के चाणक्य चन्द्रशेखर अजीत सिंह के मुद्दे को उभारकर ऐसी ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे उन्हें एक वर्ष अपने पद पर बने रहने का बोनस और मिल जाये।

अजीत सिंह को उंगलियों पर नचाने की बात सुनकर आगबबूला हुए यशवंत सिन्हा कहते हैं, "अजीत सिंह किसी के हाथ कठपुतली क्यों बनेंगे। ऐसा कहना उनका उपहास करना होगा। राजनीति में कोई भी कठपुतली नहीं होता। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमती गांधी हैं, जिन्होंने सबसे पहले उन्हीं महारथियों को धराशायी किया जो सत्ताहीन करने में अगुवा थे। मेरे विचार से चन्द्रशेखरजी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे।"

जनता पार्टी के एक असंतुष्ट नेता की प्रतिक्रिया है "शहंशाह अकबर ने राजा मानसिंह की पुत्री से शादी तो जरूर की थी, किंतु उसे हिंदुस्तान की महारानी बनाया था।" उनका स्पष्ट संकेत चन्द्रशेखर द्वारा अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की ओर था।

प्रश्न यह उठता है कि जनता पार्टी में इस विरोध का दायरा क्या है? पार्टी महासचिव श्री सिन्हा के अनुसार विरोध का यह तूफान असलियत

उत्तर प्रदेश में विलय का असर

जनता पार्टी के विलय-विरोधी नेता यदि शांत हो गये, तो जपा और लोकदल-अ के एकीकरण से उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से अजीत सिंह व चन्द्रशेखर दोनों की राजनीतिक ताकत बढ़ जायेगी। उत्तर प्रदेश ही मूल रूप से दोनों का कार्यक्षेत्र रहा है। जनवरी के अंत में चौ० अजीत सिंह ने जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर के दौरे किये। आजमगढ़ की सभा विशालतम थी। गाजीपुर में उनका शानदार स्वागत हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जाने-माने यादव नेता चौ० अजीत सिंह के साथ हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव, कैलाशनाथ यादव, कालीचरण यादव, शारदा यादव, नरसिंह यादव और आशाराम यादव आदि पूर्व सरकारों में मंत्री रह चुके सभी नेताओं ने अपने को अजीत सिंह के साथ जोड़ रखा है। ऐसी हालत में चन्द्रशेखर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्यमवर्गीय किसानों में अपनी साख जमाने में काफी आसानी होगी। अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में यादवों के वोट से वंचित चन्द्रशेखर ने काफी सोची-समझी राजनीतिक चाल चली है। चौ० अजीत सिंह ने भी अपने एक वर्ष के राजनीतिक जीवन में यह सिद्ध किया है कि उनमें राजनीति की एक सूझ-बूझ, निष्ठा और लगन की कोई कमी नहीं है। जीवन के बेहतरीन क्षण अमरीका में बिताये एक कम्प्यूटर इंजीनियर से किसी को यह अपेक्षा नहीं थी कि लोकदल से निष्कासित कर दिये जाने, हरियाणा के चुनाव में सम्पूर्ण रूप से परास्त हो जाने और लोकदल के सभी सूबाई मनसबदारों द्वारा त्याग दिये जाने के बावजूद वह राजनीति में टिके रहेंगे। इन सारी विपरीत स्थितियों में वह दल की नाव चलाते रहे। उन्होंने मेरठ से पदयात्रा कर, १२ अक्तूबर को हताशा और निराशा के क्षणों में लखनऊ में एक विशाल रैली करके अपने विरोधियों को यह जता दिया कि वे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शक्ति हैं।

मेरठ मण्डल में टिकैत के नेतृत्व में चलनेवाले किसान आंदोलन से भी उनकी राजनीतिक ताकत में कोई कमी नहीं आयी है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की ताकत से सर्वेसर्वा बने प्रदेश के विरोधी दल के नेता मुलायम सिंह यादव को धूल चटायी। इनके विधायकों को तोड़ लेने की मुलायम सिंह की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आज भी प्रदेश की विधानसभा में लोकदल-अ के साथ ५७ सदस्य हैं। बहन सरोज की आकस्मिक मृत्यु से एक सीट कम हुई। जनता पार्टी के २१ सदस्य हैं। इन दोनों दलों ने एकता स्थापित कर छोटे-मोटे दलों में भी यह भाव पैदा कर दिया है कि वे इसी एकीकृत दल में विलीन हो जाये। १२ मार्च को संजय मंच ने भी अपने अस्तित्व को जनता पार्टी में विलीन कर लिया। मंच के विधानसभा में दो सदस्य हैं। इस एकता की आंधी से कांग्रेस-ज अपने को अलग नहीं रख सकता। कांग्रेस-ज के नेता रामशंकर कौशिक ने भी अपने दल को जनता में विलीन करने का निश्चय कर लिया है। इनके चार विधायक हैं। इस तरह प्रदेश विधानसभा में जनता पार्टी की संख्या ८३ हो जायेगी। साथ ही आधे दर्जन निर्दलीय सदस्यों ने भी नवगठित जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य होने की अर्जी दे दी है। ■

नहीं अखबारों की देन है। किंतु जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीजू पटनायक मानते हैं कि एकीकरण की इस प्रक्रिया में स्वयं पार्टी नेतृत्व की पांत विभाजित हो गयी है। असंतुष्ट अपने जिन नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में पार्टी अध्यक्ष के करीबी लोगों का कहना है कि जहां तक श्री हेगड़े का प्रश्न है, उनके लिए कर्नाटक के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अन्य भूमिका निभाना अपनी ही सरकार को दांव पर लगाने की कीमत पर संभव है। इसी प्रकार बीजू पटनायक भी उड़ीसा के प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में इतने अधिक व्यस्त हैं कि उनको छोड़ना पार्टी के अच्छे खासे जनाधार को गंवाना होगा। रही बात मधु दंडवते की, तो वह हमारे सर्वाधिक कुशल, चर्चित, सांसद और सिद्धांतकार हैं और पार्टी संगठन के अगुवा के रूप में उनकी यह भूमिका मद्धिम हो जायेगी।

जनता पार्टी के विद्रोहियों के एक नेता ने 'माया' से बातचीत में कहा कि विलय का वर्तमान स्वरूप अमान्य है और संशोधन आवश्यक है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। विलय फार्मूले में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। विलय ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे पार्टी के अपने ही शक्ति संतुलन समाप्त हों तथा परस्पर संशय-संघर्ष का माहौल बना रहे। इसीलिए विद्रोही लगातार कार्यकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं।

क्या चन्द्रशेखर अपने फैसले पर अटल रहेंगे और पार्टी में खुली बगावत को दावत देंगे? जहां तक खुली बगावत और पार्टी विभाजन की बात है, उसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है। कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के मामले में भी चन्द्रशेखर के समर्थकों का वर्चस्व है। वैसे भी, विलय और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पर्दे के पीछे से तीरंदाजी करनेवाले नेता इतनी हद तक आगे नहीं जायेंगे, जिससे विघटन की नौबत आये और विपक्षी एकता का ढिंढोरा पीटने वालों के मुंह पर कालिख लगे।

> अतः भावी चुनाव के दौरान चंद्रशेखर के लिए आवश्यक हो गया था कि अपनी छवि बनाये रखने के लिए पद-त्याग तो करें, किंतु अपनी शक्ति और प्रभाव पूर्ववत बरकरार रखें। इसका सहजतम रास्ता यही था कि लोकदल-अ का विलय और अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष पद देकर वह अपनी मनोकामना पूरी करें।

यही हाल अन्य विपक्षी दलों का है। चन्द्रशेखर ने उनके सामने सीमित विकल्प प्रस्तुत कर दिया है। विपक्षी दल न तो विलय का विरोध कर सकते हैं, न अजीत सिंह की नियुक्ति का। भले ही भीतर-भीतर उनके मन में इसके विपरीत भाव क्यों न पल-बढ़ रहे हों। चन्द्रशेखर ने जिस ढंग से चाल चली है, उससे विरोध और असंतोष चाहे जितना अधिक क्यों न हो, किंतु इसका लाभ अंततः चन्द्रशेखर की अपेक्षा अजीत सिंह को प्राप्त होगा, क्योंकि सहानुभूति की लहर उनके साथ ही होगी। खासकर इसलिए कि विलय का प्रस्ताव भले ही अजीत सिंह की ओर से आया था, किंतु उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव जनता पार्टी की ओर से आया था। अजीत सिंह ने विलय को बिना शर्त माना है और इस रस्साकशी में उन्हें बेकार भागीदार बनाया जा रहा है। विलय के बारे में मधु दंडवते का मत है, "इस विलय से अंततः न सिर्फ वर्तमान संकट के बादल छंटेंगे, बल्कि बेहतर विपक्षी एकीकरण भी होगा।"

विलय के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस-स नेता व सांसद के०पी० उन्नीकृष्णन ने 'माया' से कहा, "यह विलय जनता पार्टी और लोकदल-ब का निजी मामला है। इस पर किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। किंतु जिस ढंग से इसे क्रियान्वित किया गया है और फलस्वरूप जनता पार्टी में खुला विरोध प्रदर्शित हुआ है उससे विपक्ष की छवि उज्ज्वल होने की जगह धूमिल हुई है और विश्वसनीयता को धक्का पहुचा है।"

विपक्षी की छवि धूमिल होने की सबसे अधिक हानि विपक्ष की ज्वलन्त मुद्दों की राजनीति को हुई है। नेताओं के निजी टकराव से नीतियां फिलहाल हाशिये पर आ गयी हैं। असंतुष्टों का सबसे बड़ा आरोप भी यही है कि कांग्रेस के वंशवाद को अपनाकर जातिवाद की ओर बढ़ाया गया यह कदम जपा के लिए आत्मघाती होगा। जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने इस पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा, "जातिवाद के गर्त से हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे। एक क्षेत्रींय दल से अलग हुए समूह के एक नौसिखिये नेता को यह गुरु-गंभीर पद देने में निश्चय ही जातीय-समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया होगा।" लोकदल-अ का उ०प्र० और बिहार की तीन पिछड़ी जातियों कुर्मी, जाट और यादवों पर सर्वाधिक प्रभाव है। ऐसा माननेवालों की भी कमी नहीं है कि इसी वोट बैंक को हथियाने के लिए विचारधारा और सिद्धांतों को तिलांजलि दी गयी है। इसका दूरगामी परिणाम वस्तुतः जनता पार्टी के लिए ही नहीं, समूचे विपक्ष के लिए हानिकर होगा।

बहरहाल, यह तो भविष्य ही बतलायेगा कि जपा-लोकदल-अ के विलय से कांग्रेस-इ के विरुद्ध विपक्षी दलों का मार्ग प्रशस्त होगा या इस विलय के फलस्वरूप जनता पार्टी के नेताओं में उभरा अन्तर्विरोध जनता पार्टी को ही बिखेर देगा।

—रंजना कक्कड़

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

संजय मंच—जपा विलय

मेनका गांधी का क्या भविष्य होगा ?

आखिरकार १२ मार्च १९८८ को अमेठी के रामलीला मैदान में दस हजार के मजमे के बीच मेनका गांधी की पार्टी राष्ट्रीय संजय मंच का विलय जनता पार्टी में हो गया। विलय के गवाह के रूप में मंच पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, जपा नेता बीजू पटनायक, बापू कालदाते, उप्र जनता विधायक दल के नेता कुंवर रेवतीरमण, प्रादेशिक अध्यक्ष ओमप्रकाश श्रीवास्तव, संजय मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अकबर अहमद 'डम्पी', संयोजक विनोद त्रिपाठी, गोरखपुर के विधायक वीरेन्द्र प्रताप शाही और महामंत्री रामप्रवेश मुख्य रूप से विराजमानं थे।

कई बड़े और छोटे नेताओं के भाषण के बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर और संजय मंच की अध्यक्ष मेनका गांधी के बीच झंडे का आदान-प्रदान हुआ। झंडों के आदान-प्रदान के साथ ही मेनका ने अपने 'पुराने घर' राष्ट्रीय संजय मंच को छोड़ दिया और 'एक सपर्पित कार्यकर्ता' के रूप में जनता पार्टी के 'नये घर में' बिना किसी संशय और संकोच के पदार्पण किया। पुराने घर से नये घर में आने की रस्म तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच उल्लासपूर्ण माहौल में अदा की गयी। कहीं किसी भी कोने से विरोध का स्वर नहीं फूटा, जिसकी आस मंच से दो साल पहले निकाले गये वरिष्ठ महासचिव जेएन मिश्र ने की थी।

दरअसल, विलय के तीन दिन पहले से ही मिश्र ने विलय विरोधी स्वर निकालने शुरू कर दिये थे। यहां तक कि १२ मार्च को उन्होंने अमेठी के पास गौरीगंज कस्बे में 'समानांतर सम्मेलन' की घोषणा कर दी थी और उस पर अमल भी किया। अमल से पहले ही उन्होंने मेनका गांधी और अकबर अहमद को राष्ट्रीय संजय मंच से निकाल दिया और मंच के डंका में विलय का एलान कर दिया। अलबत्ता, विरोध के नाम पर गौरीगंज और अमेठी में बड़े-बड़े रंगीन पोस्टर चिपकाये गये थे। इनमें निवेदक और

मंच के वरिष्ठ महासचिव की हैसियत से जेएन मिश्र ने लिखा, "संजय समर्थकों सावधान! संजय गांधी की कर्मभूमि अमेठी में राष्ट्रीय संजय मंच और जनता पार्टी के प्रस्तावित विलय का बहिष्कार क्यों?" इसके साथ ही पोस्टर में इस क्यों का जवाब दिया गया था—"संजय गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात, संजय गांधी के साथियों के साथ विश्वासघात, संजय गांधी के दुश्मनों से सांठगांठ।"

भव्य स्वागत : श्री मिश्र की गतिविधियों से यह आशंका उत्पन्न हुई थी कि लखनऊ से अमेठी तक के सवा सौ किलोमीटर के रास्ते में मिश्र समर्थक और इंकाई काले झंडों के साथ प्रदर्शन कर कुछ गड़बड़ी पैदा न कर दें। मंच कार्यकर्ताओं और मिश्र समर्थकों में झड़प हो जाने का भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था। लेकिन सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और सब ठीक-ठाक हो गया। उलटे मेनका गांधी, रामकृष्ण हेगड़े और बीजू पटनायक के साथ ५० कारों और जीप में चल रहे विलय समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं और नेताओं के काफिले का भव्य स्वागत चक गंजरिया, गोसाईगंज, गंगागंज, मुंशीगंज, चिवल, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, इन्हौना, जगदीशपुर, कमरौली, जाफरगंज, हरिमऊ, जामों और गुलालपुर आदि दो दर्जन से अधिक गांवों और कस्बों में भारी भीड़ ने किया। रास्ते भर में लगभग एक सौ तोरण द्वार सजाये गये थे। इस स्वागत के लिए जनता घंटों से इंतजार कर रही थी। अमेठी में बलिया से पहले पहुंचे चन्द्रशेखर और ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने सभास्थल के पास सरकारी अतिथिगृह में मेनका गांधी और उनके काफिले की अगवानी की। सभा मंच पर सभी नेताओं के पहुंचने के बाद एक घंटे के अन्दर ही विलय की औपचारिकता पूरी हो गयी।

आखिर मेनका गांधी ने विलय के लिए अमेठी को ही क्यों चुना? विलय तो दिल्ली या लखनऊ में भी हो सकता था? हेगड़े के अनुसार, "मेनकाजी ने यह स्थान शायद इसलिए चुना कि हम जान सकें कि अमेठी की जनता में उनके लिए कितना प्यार है और वह उन पर कितना भरोसा रखती है।" उन्होंने आगे बताया, "रास्ते में जनता की तरफ से उन्हें मिले प्यार और अमेठी की भीड़ ने साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र की जनता का विश्वास राजीव में नहीं मेनका में है।"

खुद मेनका ने भावुक होकर बताया, "जब ग्यारह साल पहले मैं बहू बनकर आयी थी, तब अमेठी की जनता ने मुझे संजय गांधी की पत्नी के रूप में जाना था। बाद में संजयजी की असहाय विधवा के रूप में आयी। फिर मंच के अध्यक्ष के रूप में। तीनों ही रूपों में अमेठी की जनता से मुझे अपार स्नेह और प्यार मिला। विलय के समय मैं इस प्यार को भला कैसे ठुकरा सकती थी।"

बहरसूरत, अमेठी को चुनने के पीछे मेनका का एक छिपा मकसद राजीव गांधी को यह बता देना था कि वह यहां से आगामी लोकसभा के चुनाव में उनका विरोध कर सकती हैं। इसके साथ ही जनमोर्चा के स्थानीय विधायक डा० संजय सिंह को हलकी सी यह समझ भी देना था कि सत्ता सहयोग से उनकी जमानत जब्त करवा देने के उनके हथकंडे के बाद भी अमेठी की जनता में उनके लिए प्यार बाकी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इंका के प्रभावी मंत्री होने के नाते राजीव गांधी को जिताने में डा० संजय सिंह ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी थी। शायद इसी रणनीति के तहत मेनका गांधी और मंच के नेता डम्पी ने अब विपक्ष में होते हुए भी विलय रैली के लिए संजय सिंह के सहयोग की पेशकश को नजरंदाज कर दिया था।

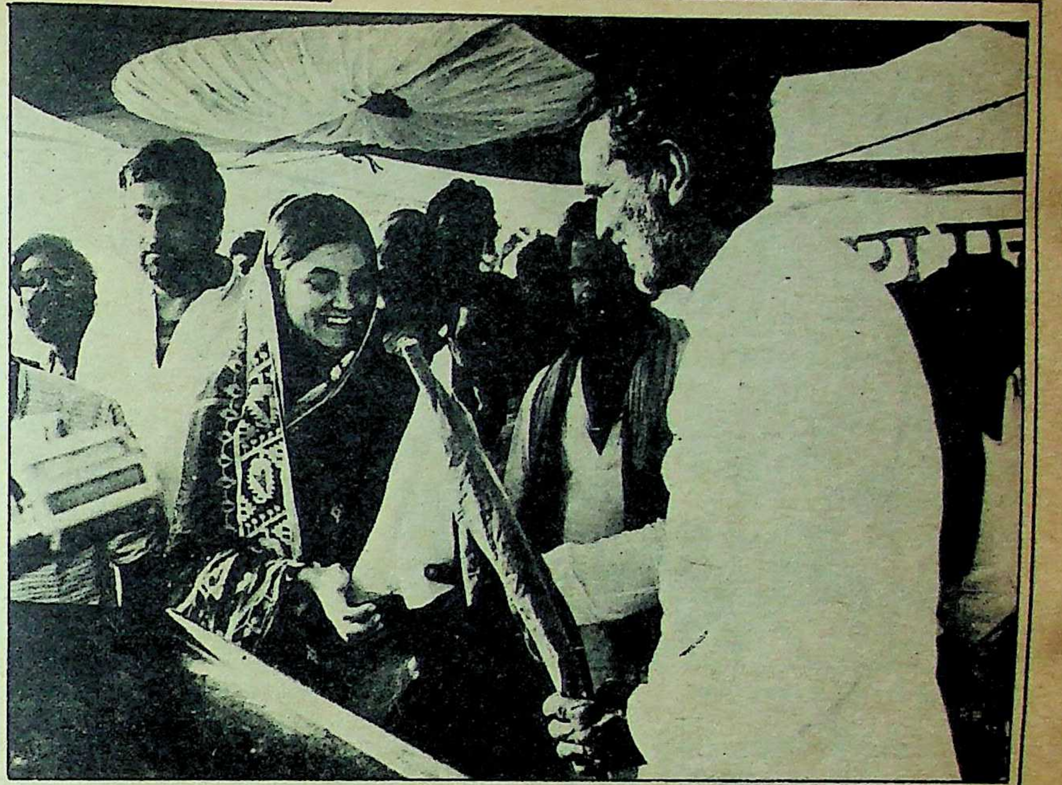

दुश्मनों से दोस्ती : विलय समारोह में झंडा बदलते चंद्रशेखर और मेनका गांधी

मंच के वरिष्ठ नेता विनोद त्रिपाठी का कहना है, "संजय सिंह से सहयोग न लेने के पीछे हमारी यह भावना भी रही है कि हम यह साबित कर सकें कि मंच के पीछे अमेठी की जनता अब भी खड़ी है।" इस सिलसिले में मजेदार तथ्य यह है कि संजय सिंह ने विलय समारोह में सहयोग देने और खुद को शामिल करने के लिए कई माध्यम से अपनी इच्छा मेनका गांधी तक पहुंचवाई थी, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने लखनऊ में बैठे-बैठे अखबारों से यह भी प्रचार करवाया था कि जनमोर्चा मंच की रैली की सफलता के लिए काम कर रहा है। जनमोर्चा से सहयोग न लेने का एक कारण यह भी हो सकता है कि, जनता पार्टी, जनमोर्चा और लोकदल-अ के राष्ट्रीय मोर्चे में शामिल होने की मंच की पेशकश पर जनमोर्चा की बेरुखी से मेनका गांधी नाराज थीं। उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी, जब २९ मार्च, १९८२ को वह अरुण नेहरू के जोड़-तोड़ के कारण प्रधानमंत्री निवास से निकाली गयी थीं।

एक और सवाल उभर कर सामने आता है कि १२ मार्च का दिन ही विलय के लिए क्यों तय किया गया? इतनी जल्दी भी क्या थी? २८ मार्च तक तो रुका ही जा सकता था। इस तारीख को १९८२ में लखनऊ में संजय विचार मंच का गठन किया गया था। फिर ३ अप्रैल तक का इन्तजार भी किया जा सकता था, जब १९८३ में दिल्ली में विचार मंच को राष्ट्रीय संजय मंच के रूप में राजनीतिक दल बनाया गया था? इन सवालों का एक ही जवाब हो सकता है कि मेनका और डम्पी को विलय की हड़बड़ी थी। वे नहीं चाहते थे कि जार्ज फर्नांडीस की तरह जनता पार्टी का कोई नेता विलय का फिर से विरोध शुरू कर दे और एक बार फिर विलय का सवाल गड़बड़ा जाये। जनता पार्टी में लोकदल-अ के मिलने से पैदा हुए एकता के माहौल का भी वे फायदा उठाना चाहते थे।

मंच का उदय और अंत : २३ जून, १९८० को संजय गांधी की विमान हादसे में हुई अकाल मौत के बाद राजीव गांधी को राजनीति में उतारने के मकसद से इंदिरा गांधी के इशारे पर उनके भरोसे के लोगों, अरुण नेहरू, माखनलाल फोतेदार, आरके धवन, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आदि ने प्रधानमंत्री निवास में मेनका विरोधी अभियान छेड़ रखा था। १९८० में चुनाव के बाद लोकसभा में ३५४ इंकाई चुनकर आये थे। उनमें १८० सांसद संजय गांधी के साथ थे। यही नहीं राज्य विधानसभाओं में हर चौथे इंका विधायक की निष्ठा संजय के प्रति थी। इसी तरह दर्जनों प्रदेश इंका समितियों के अध्यक्ष और हजारों नौजवान इंकाई संजय के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। इन सबों को एक ही दिन में राजीव भक्त बना देना असंभव था। इसलिए प्रधानमंत्री निवास में मेनका गांधी का अनादर शुरू हो गया और पार्टी के अन्दर से संजयवादियों को छांटना शुरू कर दिया

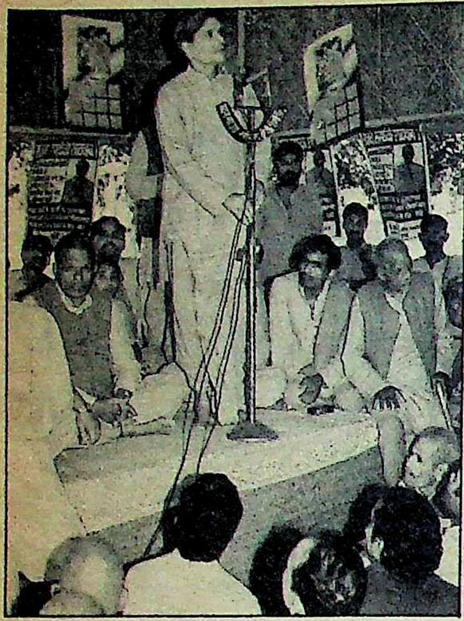

विलय का विरोध: जे०एन० मिश्र

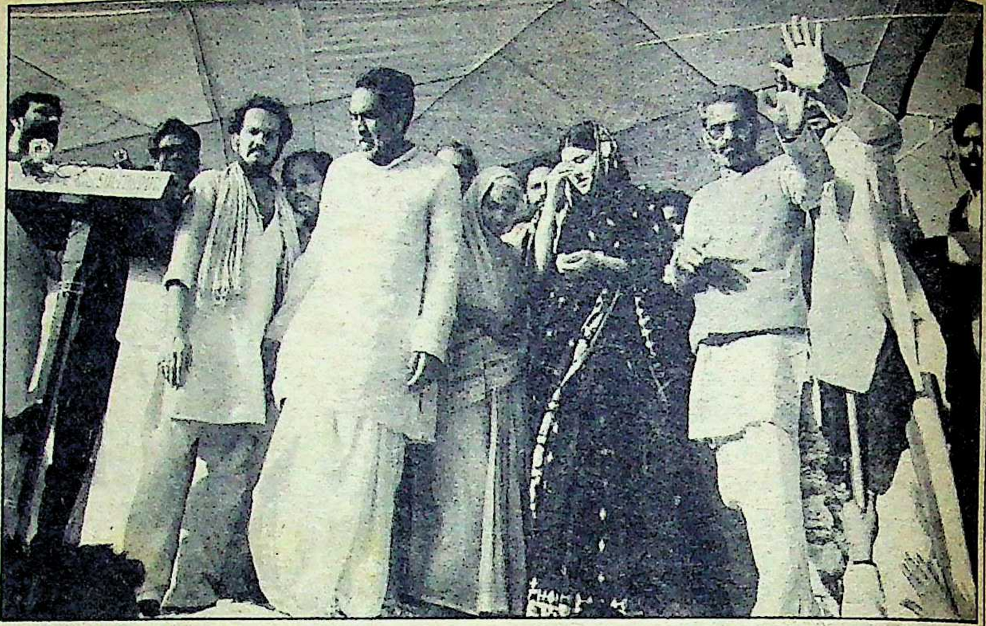

सशंकित भविष्य: विलय के बाद मंच पर अकबर अहमद डम्पी, चंद्रशेखर और मेनका गांधी

गया। इन लोगों के लिए इंका में जानबूझ कर दमघोटू वातावरण पैदा कर दिया गया। इंदिरा जी राजीव और संजय के बाद जिसे 'अपना तीसरा बेटा' कहती थीं, उस अकबर अहमद को महज इसलिए जलील किया गया कि वह संजय की विधवा मेनका का साथ न दे। डम्पी के कथनानुसार, "उन दिनों प्रधानमंत्री निवास में छोटी-छोटी सी बातों पर मेनकाजी को जलील करने की हरकतों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं संजय का दून स्कूल से दोस्त था। उन्होंने ही मुझे १९७७ में अमेठी के चुनाव में भेजकर राजनीति में उतारा था। मैं मेनकाजी के साथ घर में होने वाले अन्याय को सहन नहीं कर पाया। उबल पड़ा। एक दिन २८ जुलाई, १९८० को संजयजी के कुत्तों, शिवा और ब्रूनी के लिए बिस्कुट न मंगाने के सवाल पर मेनकाजी की हुई बेइज्जती ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उस दिन पहली बार मैंने तल्ख लहजे में इंदिराजी से अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस पर उन्होंने मुझे ताकीद दी कि दो बहुओं के मामले से अपने को अलग रखो, वरना तुम्हारा सियासी भविष्य खतम हो जायेगा। इसके बाद मैंने तुरंत वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा से अपना इस्तीफा इंदिराजी को दे दिया। और जब मेनकाजी का अपमान नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो मैंने १६ अगस्त, १९८० को प्रधानमंत्री निवास हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया।"

दरअसल, संजय विचार मंच का पहला बीज १६ अगस्त, १९८० में ही पड़ चुका था और वह नन्हा बीज २८ मई, १९८२ को लखनऊ के कैसरबाग बाराদরী में प्रस्फुटित हुआ। फिर ३ अप्रैल, १९८३ में दिल्ली में उस पौधे ने राजनीतिक बिरवा—राष्ट्रीय संजय मंच—का रूप ले लिया। अब इस पौधे का अस्तित्व पांच साल के बाद १२ मार्च को अमेठी में जनता पार्टी में विलय के साथ ही समाप्त हो गया।

भारतीय राजनीति में जितने दिनों तक मंच का अस्तित्व रहा, मेनका गांधी ने कई उतार-चढ़ाव देखे। इंदिराजी के निधन के पहले उनके पीछे जनता की बेशुमार भीड़ और नौजवानों का हुजूम कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए चल रहा था। तब यह वाक्य मशहूर था, "मेनका नाम नहीं, आन्दोलन है।" इंदिरा गांधी के प्रति व्यक्तिगत विरोध से उठी राजनीति को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही ग्रहण लग गया। अमेठी के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के मुकाबले अपनी जमानत गंवाने के साथ ही उनका हौंसला पस्त हो गया। मेनका और उनका दल राजीव गांधी का व्यक्तिगत विरोध भी करता रहा, पर इस विरोध को वह 'हमदर्दी' में बदल पाने में नाकामयाब रहा। लिहाजा, सास द्वारा विधवा बहू को घर से निकाल देने की भावना से पैदा हुई सहानुभूति का बलबला इंदिराजी की हत्या के साथ ही खतम हो गया। हत्या से उत्पन्न सहानुभूति का पूरा फायदा राजीव गांधी को मिला और इस बड़ी सहानुभूति ने 'सास-बहू की छोटी सहानुभूति' को अंधेरे में ढकेल दिया।

इसके बाद ही संजय मंच के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगने शुरू हुए। उसके सामने दो ही रास्ते बचे थे। या तो वह इंका में मिल जाये या फिर किसी बड़े दल में मिलकर विरोध की राजनीति चलायें। मेनका गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, हालांकि प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद राजीव गांधी ने घर वापसी के लिए मेनका गांधी को संदेश भिजवाया था। आपसी मेल-मिलाप के लिए जेएन मिश्र ने कोशिश भी की थी। लेकिन, मेनका गांधी के हठ और डम्पी के विरोध ने मिश्र की कोशिशों को असफलता में बदल दिया। अंततोगत्वा मिश्र को दो साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में संजय मंच से निकाल दिया गया था। इस बीच मेनका के इशारे और संजय मंच की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों के [illegible] पर डम्पी ने शहाबुद्दीन और रामकृष्ण हेगड़े की मार्फत मंच को जनता पार्टी में विलय कराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसका नतीजा अमेठी में दोनों दलों के विलय के रूप में सामने आया।

अब क्या मेनका गांधी फिर इंदिराजी के समय की तरह उभर कर सामने आयेंगी या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगी? जहां तक राजनीतिक संन्यास का सवाल है, मेनका गांधी का कहना है, "इसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब मैं अखबारों में कालम लिखने के साथ ही जनता पार्टी द्वारा दी गयी भूमिका को उसी जोश-ओ-खरोश से निभाऊंगी, जिस तरह संजय मंच के अध्यक्ष के रूप में निभाती रही हूं।" इस विलय से जनता पार्टी को कौन-सा राजनीतिक लाभ मिलेगा? इसके जवाब में चन्द्रशेखर का कहना है, "मंच के पास उत्साही नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। हमें उम्मीद है कि नौजवानों की इस टोली से राजीव विरोध की धार तेज होगी और देश में विरोध की राजनीति को बल मिलेगा।" राजनीतिक पर्यवेक्षकों का खयाल है कि अकबर अहमद के माध्यम से हिन्दी और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में मुस्लिम नौजवानों के बीच जनता पार्टी की पैठ गहरी होगी। गांधी परिवार के सदस्य के रूप में वह जनता में और खासकर महिलाओं में मेनका गांधी की छवि को भुना सकती हैं। देखना है कि जनता पार्टी मेनका गांधी, डम्पी और उनके समर्थकों को पार्टी के अन्दर किस तरह खपाती है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि राज्यसभा के होने वाले चुनाव में जनता पार्टी मेनका को अपना उम्मीदवार बनायेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह युवा जनता की अध्यक्ष भी बनायी जा सकती हैं।

—अशोक रजनीकर

छाया: मनमोहन शर्मा

मार्फत
कोशिश
दलों के

जी के
T फिर
तक
धी का
होता।
जनता
श-ओ-
च के
लय से
लाभ
हता है,
बड़ी
की इस
र देश
गा।"
अकबर
भाषी
र्टी की
रूप में
मेनका
है कि
उनके
ती है।
कता।
यी कि
पार्टी
न ऐसा
बनायी

नौकर

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यिुब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के इन्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सावधान-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

छाया :
एन० प्रसाद

ज्ञानीजी का दोहरा खेल

अब राजीव गांधी क्या करेंगे ?

राष्ट्रपति भवन छोड़ने के छह महीने बाद ज्ञानी जैल सिंह ने फिर धमाका कर दिया है। जब से उन्होंने चुनिंदा मंत्रियों और यहां तक कि राष्ट्रपति वेंकटरमण को भी 'भेड़ की खाल में सियार' का फतवा दिया है, तब से राजीव गांधी की स्थिति उन नौरत्नों से घिरे राजा जैसी हो गयी है, जिनमें से हरेक राजा की पीठ में छुरा भोंक कर सिंहासन हथियाने की फिराक में है। ज्ञानी जैल सिंह ने यह कह कर कांग्रेसियों को सन्न कर दिया है कि राजीव गांधी की गद्दी पर आर वेंकटरमण, बलराम जाखड़, पीवी नरसिम्हाराव और अर्जुन सिंह आदि आंखें गड़ाये बैठे हैं। लेकिन कांग्रेसियों को इस बात की ज्यादा चिंता है कि इस रहस्योद्घाटन के बाद राजीव गांधी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं।

राजीव गांधी की भावी रणनीति दो बातों पर निर्भर करेगी: एक, जैल सिंह ने जो रहस्योद्घाटन किया है, वह कितना विश्वसनीय है? दो, ज्ञानीजी ने अपने आप यह धमाका किया या स्वयं राजीव गांधी के खास लोगों ने उन्हें उकसा कर यह काम करवाया है?

ज्ञानीजी ने स्वयं किया है, तो इसके पीछे उनका इरादा यह हो सकता है कि प्रतिष्ठित लोगों को संदिग्ध बनाकर राजीव गांधी और उनके समर्थकों के बीच जहर घोला जाये। यदि इसके पीछे राजीव गांधी के खास लोग हैं, तो रणनीति यह हो सकती है कि जिनको राजीव गांधी अवांछित समझते हैं, उनको ज्ञानीजी के माध्यम से बदनाम करवा कर पार्टी से उनका सफाया कर दिया जाये। ज्यादातर कांग्रेसी दोनों ही संभावनाओं को स्वीकार करके चल रहे हैं।

जाहिर है, यदि ज्ञानीजी ने कमर कस ली है कि राजीव गांधी की नाक में दम किया जाये, तो फिर उन्होंने अपने पुराने विचार बदल लिये हैं कि "वह (राजीव गांधी) मेरे पास मासूम चेहरा बनाकर हाथ जोड़े आया था," इसलिए माफ कर दिया। उन्हें यह कहते सुना भी गया है कि वह सुधरा नहीं है। या फिर ज्ञानीजी ने राजीव गांधी से हाथ मिला लिये हैं, ताकि वह इंदिरा गांधी के बचे-खुचे वफादारों से मुक्ति पाकर 'इंदिरा गांधी कांग्रेस को' 'राजीव गांधी कांग्रेस' में तब्दील कर सकें।

ज्ञानीजी के रहस्योद्घाटन पर सत्ता पक्ष की ही तरह विपक्ष भी भौंचक है। विपक्षी जानते हैं कि ज्ञानीजी को उनसे कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन यदि वह (ज्ञानीजी) प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, तो उनको लाभ मिल सकता है। विपक्ष व्यामोह में है कि ज्ञानीजी के रहस्योद्घाटन को वह ब्रह्म वाक्य माने या इसे यह समझ कर आया-गया कर दिया जाये कि यह तो ज्ञानीजी का, अपनी अहमियत जताने का, एक और हथकंडा है— ताकि प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोने वाले लोग समझें कि ज्ञानीजी बड़े काम के आदमी हैं।

यदि ज्ञानीजी प्रधानमंत्री का पत्ता चल रहे हैं, तो फिर राजीव गांधी के लिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यदि वर्तमान राष्ट्रपति, लोकसभाध्यक्ष और मंत्रियों के व्यवहार के बारे में वह जो कुछ कह रहे हैं, उसमें सत्यांश है, तो फिर राजीव के पास बहुत कम विकल्प बच जाते हैं। देश की राजनीति और अपने भविष्य को तय करने वाले जो मुद्दे उनके सामने हैं, वे इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रपति वेंकटरमण और लोकसभाध्यक्ष को संदेह से वह कैसे मुक्त करें?
- क्या व्यक्तिगत आश्वासन ही काफी है या उनसे यह कहें कि वे सार्वजनिक रूप से ज्ञानीजी की बात का खंडन करें? लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि यदि खंडन के बाद ज्ञानीजी अपनी बात को फिर पुष्ट करने पर तुल गये, तो क्या होगा?
- क्या पीवी नरसिम्हाराव जैसे मंत्रियों को वफादारी सिद्ध करने के लिए इस्तीफा देने के लिए कहा जाये?
- क्या पार्टी के विभाजन का खतरा उठा कर बड़ा छंटनी-अभियान चलाया जाये?
- क्या वह इस घोषणा के साथ नये चुनाव करवायें कि अब तक वह दगाबाज साथियों से घिरे हुए थे?

राष्ट्रपति भवन
के बाहर रहने पर भी हंगामा:
ज्ञानी जैल सिंह

छाया:
सुनील सक्सेना

प्यासे लेन-देन

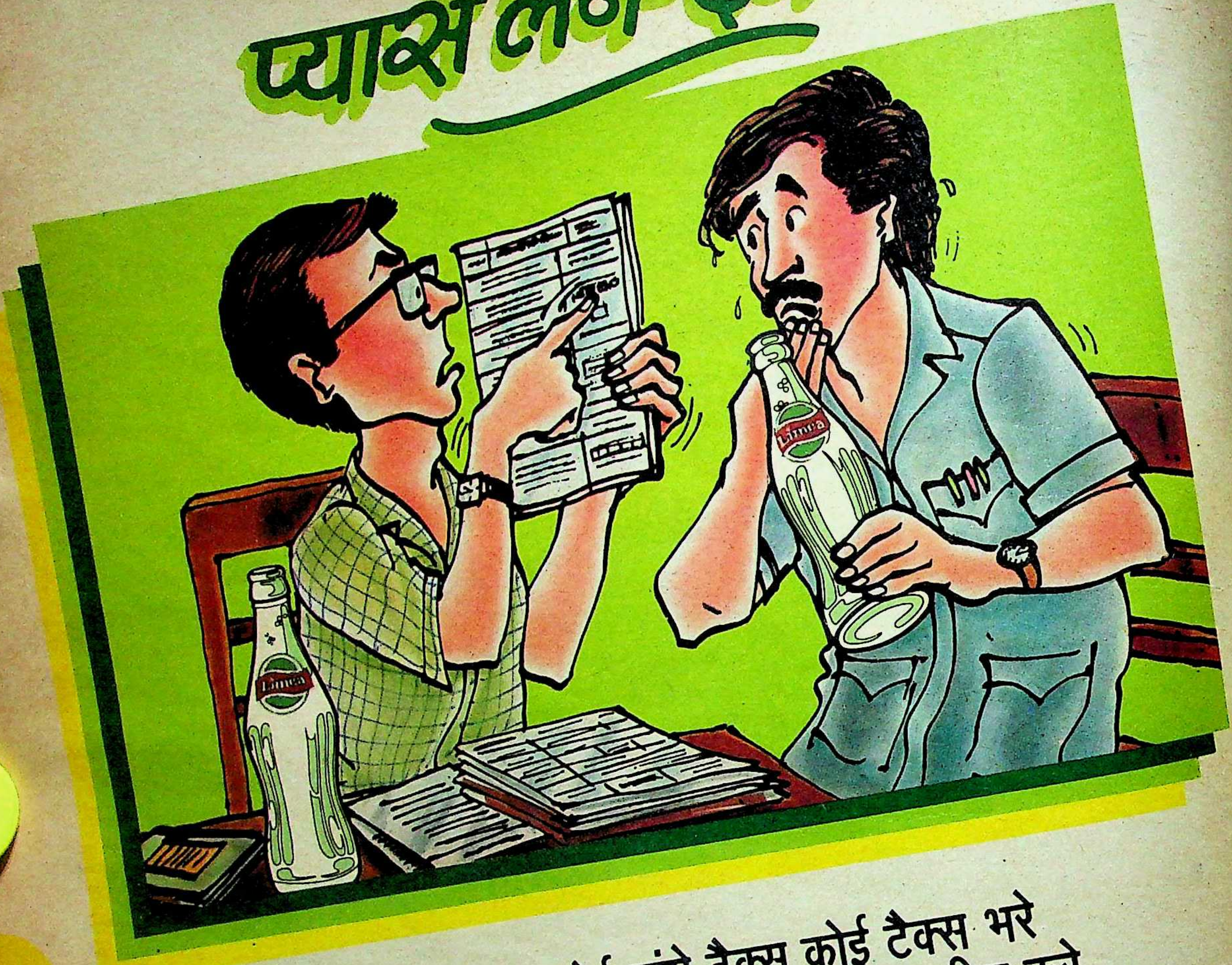

कोई मांगे टैक्स कोई टैक्स भरे
लिम्का बुझाये प्यास मूड ठीक करे

जब आप इनकम टैक्स के लिए अपनी आमदनी का हिसाब लगाते-लगाते या किसी और की आमदनी का हिसाब करते-करते थक कर प्यास से बेहाल हो जायें तब आयसोटॉनिक सॉल्ट वाले किटाणुरहित लिम्का की बोतल उठायें और अपनी प्यास बुझायें.

Limca
Limca
Limca®
नींबू जल-सा मज़ेदार पेय
ठंडा बर्फीला पिए-पिलाएं

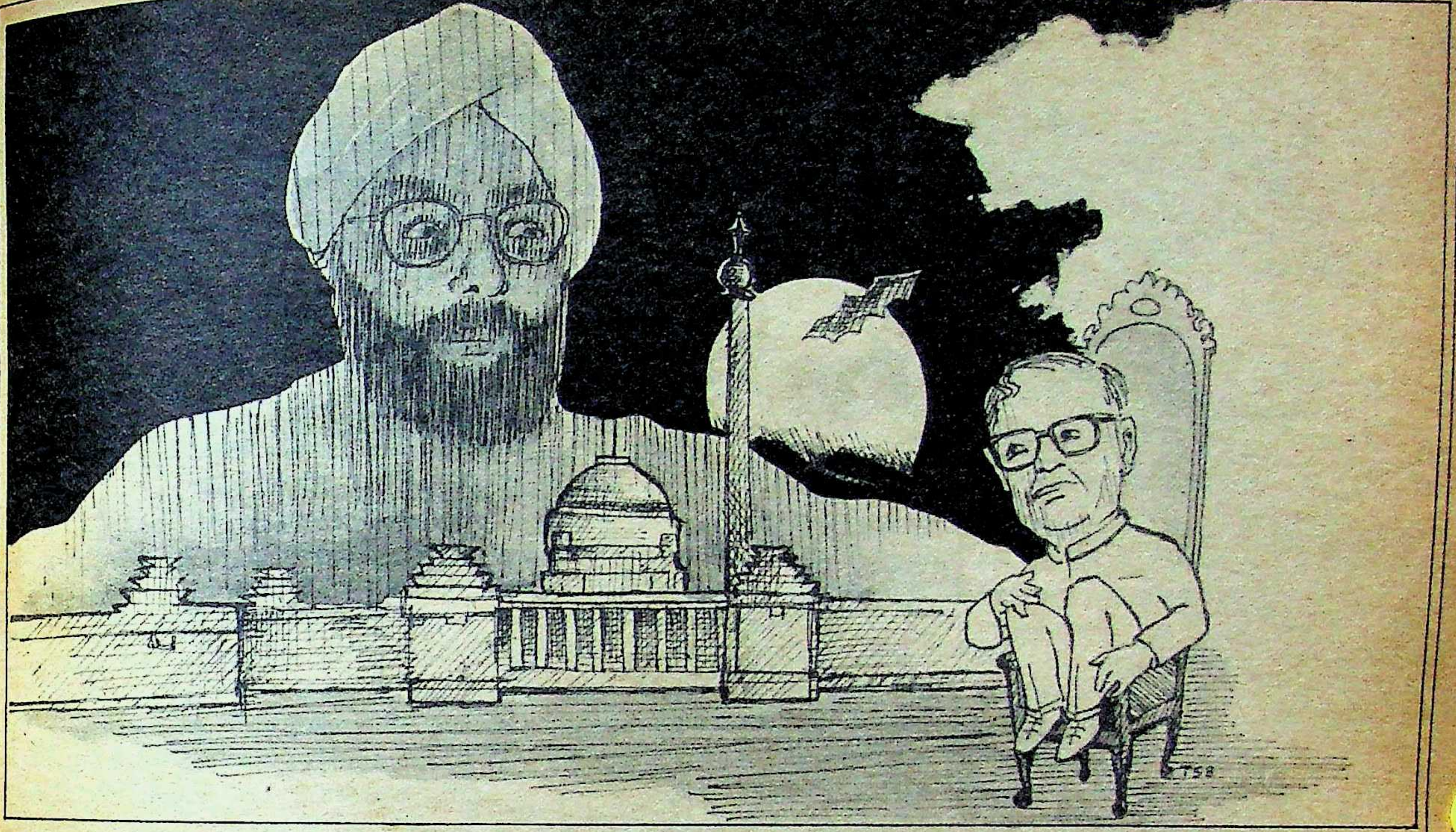

"असलियत का पता लगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।" लोकसभाध्यक्ष बलराम जाखड़ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब लोकसभा में ज्ञानी जैल सिंह को दुबारा चुनाव लड़ने के लिए ३०-४० करोड़ रुपए देने की पेशकश का मामला उठा। मामले को गंभीर मोड़ देते हुए श्री जाखड़ ने यह भी जोड़ा, "क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए यह (जांच) जरूरी है।" इस पर प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, "मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा।" वह बूटा सिंह की ओर मुखातिब हुए और कहा कि वह पता लगायें कि जैल सिंह के सामने ३०-४० करोड़ का प्रस्ताव किसने रखा, यह धन कहां से आना था और इसका कहां क्या उपयोग होना था? दरअसल, सुझाव ऐसी जांच करने का था, ताकि उन लोगों की शिनाख्त हो सके, जिन्होंने यह धन जुटाया था। इशारा था कि यह धन विदेशी था और इससे उन भूतपूर्व मंत्रियों के विदेशी सूत्र जुड़े हैं जो अब विपक्षी बेंचों पर बैठे हैं। बेशक साफ इशारा 'वीपी सिंह ऐंड कंपनी' की ओर था। सत्तापक्ष के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती थी। जैल सिंह ने खुद ही अपने जाल में फंसकर, राजीव गांधी को अंतिम रूप से यह सिद्ध करने का मौका दे दिया था कि वीपी सिंह की विदेशी ताकतों से सांठगांठ है।

तूल: २ मार्च को दूरदर्शन ने लगभग दो मिनट तक अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया कि सरकार सांसदों को खरीदने (दूसरे शब्दों में भ्रष्ट करने) के लिए कुछ लोगों के पास उपलब्ध 'नाजायज दौलत' के आरोप की जांच करने जा रही है। कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद पहली दफा ज्ञानीजी का महत्वपूर्ण समाचारों में उल्लेख हुआ। सरकार और राजनेताओं की रुचि एकमात्र इस बात में केंद्रित हो गयी कि यह धन-स्रोत कहां है और इस मामले के जरिये वे अपने किन राजनीतिक विरोधियों को बलि का बकरा बनायें। यह फिक्र कहीं नहीं दिखायी दी कि इस आरोप से यह धारणा बनी है कि सांसद खरीद-फरोख्त की वस्तु हैं। मामला दो धड़ों के बीच सीधी टक्कर का बनता नजर आया—एक ओर राजीव और उनके अनुयायी और दूसरी ओर विपक्ष। विपक्ष की हालत बदतर हो गयी थी, क्योंकि ज्ञानीजी ने अपने आपको ऐसा मामला बना दिया था, जिससे विपक्ष की बदसूरत मूरत गढ़ी जा सके। परिणामस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य विपक्षी नेताओं का एक शिष्टमंडल जैल सिंह से मिला और उन पर जोर डाला कि वह नाम खोलें, अन्यथा सारी गैरकांग्रेसी पार्टियों पर कालिख पुत जायेगी।

चौंकानेवाला मोड़: ९ मार्च, १९८८ को इस मामले ने सनसनीखेज मोड़ उस समय ले लिया, जब 'टाइम्स आफ इंडिया' में सुभाष किरपेकर की रिपोर्ट पहले पृष्ठ पर शाया हुई। सारे विवाद को कांग्रेस के अंदरूनी मामले का रूप देकर इस रिपोर्ट में कहा गया कि ज्ञानी जैल सिंह जो कुछ कह रहे हैं, उस पर कांग्रेस का कोई नेता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं—विपक्ष में भी विश्वास करनेवाले नेताओं की संख्या गिनी-चुनी है। लेकिन रिपोर्ट में पहली दफा कुछ नाम उछलकर आये। कहा गया कि ४० करोड़ रुपए की पेशकश करनेवाले नेता पीवी नरसिम्हाराव, पी. शिवशंकर, भजनलाल और बलराम जाखड़ थे। ये नाम बतानेवाले खुद जैल सिंह बताये गये। इस रिपोर्ट के बाद कयास भिड़ाने का अटूट सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेसी हलकों में कुछ मंत्रियों और उनके गुट के सांसदों के बारे में चर्चाएं शुरू हो गयीं।

इसके बाद पहली दफा यह संदेह जन्मा कि ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री के इशारे पर खेल रहे हैं, जिससे राजीव गांधी महत्वाकांक्षियों और प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगा सकें। नतीजतन कांग्रेसियों में अफरा-तफरी मच गयी और अपने आकाओं को बचाने और विरोधियों को फंसाने की तिकड़म शुरू हो गयी। ज्ञानीजी ने इस स्थिति का लाभ उठाया और 'इलस्ट्रेटेड वीकली' के संपादक प्रीतीश नंदी को बताया कि उनके पास एक कनिष्ठ मंत्री आया था और उसने वीपी सिंह, अरुण नेहरू, वीसी शुक्ल और आरिफ मोहम्मद खान का नाम लेने के एवज में 'घूस' देने की पेशकश की थी। जैल सिंह ने विश्वास में आकर यह भी बता दिया कि वह मंत्री राजेश पायलट थे।

ज्ञानीजी पर संदेह: ज्ञानी जैल सिंह का यह बताना आश्चर्यजनक है। यह 'रहस्योद्घाटन' इसलिए विश्वसनीय लगता है, क्योंकि इससे पहले ज्ञानी जैल सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि दो मंत्री—बूटा सिंह और राजेश पायलट—अकसर राष्ट्रपति भवन में आकर उनसे कहा करते थे कि वह राजीव गांधी के प्रति अपना गुस्सा थूक दें—"दोनों, दोनों तरफ बैठ कर मेरे हाथ-पैर पकड़ लिया करते थे।"

सवाल उठता है कि जब राजीव गांधी [illegible]

विश्वासपात्र या... : नरसिम्हाराव, वेंकटरमण, बलराम जाखड़ के साथ प्रधानमंत्री

राजीव के अब भी आंख कान : फोतेदार शपथ लेते हुए

जानते थे कि जो लोग उनको छोड़ गये हैं, वही असली मुजरिम हैं, तो फिर उनको ज्ञानीजी के पास पायलट के भेजने की क्या जरूरत थी ? जांच से यह बात अपने आप साफ हो जाती। "पायलट को इसलिए भेजा गया था, ताकि यह प्रलाप जारी रहे कि 'वीपी सिंह ऐंड कंपनी' को जैल सिंह ने मूर्खतावश संकट में डाल दिया है और ज्ञानीजी दिल्ली दरबार की ओर से कुछ नहीं कर रहे," यह कहना है पार्टी के उस कुंठित पदाधिकारी का, जिस पर आजकल यह आरोप लगाया जाता है कि वह अकसर विवादास्पद मामलों में बेवजह अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के इरादों पर संदेह एक वरिष्ठ मंत्री की बातों से भी होता है। उनका कहना है कि 'टाइम्स आफ इंडिया' की रिपोर्ट में पीवी नरसिम्हाराव और अन्य लोगों के नाम माखनलाल फोतेदार के इशारे पर दिये गये हैं। फोतेदार के बारे में यह माना जाता है कि कैबिनेट मंत्री का पद पाने के बावजूद वह राजीव गांधी के राजनीतिक आंख-कान हैं। यदि यह बात सही है, तो फोतेदार राजीव गांधी या उनके किसी करीबी व्यक्ति की सहमति के बिना नाम नहीं उछाल सकते थे।

इसी कारण पार्टी के लोग ज्यादा चिंतित नहीं हैं। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ऐसे विवादास्पद मसले को 'संडे' के माध्यम से छेड़ने के कारण भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एम जे अकबर के कारण इस पत्रिका पर राजीव गांधी की छाया मानी जाती है। वैसे भी अब जैल सिंह का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। इसलिए कांग्रेस-इ के कुछ लोगों को यह लगता है कि जैल सिंह प्रधानमंत्री के सलाहकारों की डोर से बंधी कठपुतली की तरह बोल रहे हैं। एक बात और गौरतलब है। वह यह कि जिन लोगों के नाम लिये जा रहे हैं, उनमें वे मंत्री हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे महत्वाकांक्षी होने व कांग्रेस संस्कृति के विपरीत अधिक शक्ति जुटाने के कारण राजीव गांधी की नजरों से उतरे हुए हैं। नरसिम्हाराव के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद वह अस्थायी प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी थे। हाल में उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह बोफोर्स और वीपी सिंह के मामले से निपटा गया, उससे नरसिम्हाराव इत्तफाक नहीं रखते। नरसिम्हाराव से प्रधानमंत्री इसलिए भी नाराज माने जाते हैं कि उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। शिवशंकर के बारे में भी ऐसी बात कही जा रही है। उनसे राजीव इसलिए खफा माने जाते हैं, क्योंकि एलएम थापर और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एनटीआर के मामलों में उनकी वैसी भूमिका नहीं रही, जैसी प्रधानमंत्री चाहते थे।

यही स्थिति राष्ट्रपति वेंकटरमण के बारे में मानी जाती है, जिनका नाम जैल सिंह ने प्रीतीश नंदी के सामने लिया है। श्रीलंका नीति से तो वेंकटरमण नाराज बताये ही जाते हैं, उनको इस बात का रंज भी है कि राजीव गांधी ने तमिलनाडु की राजनीति में मूपनार और पी चिदंबरम को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है।

कांग्रेसियों की चिंता : ये बातें कांग्रेसी सांसदों को कितना परेशान किये हैं, यह बात इस तथ्य से साबित हो जाती है कि जब संसद में 'पंजाब इमरजेंसी बिल' पर तनावपूर्ण बहस चल रही थी, तो उस समय कांग्रेसी सांसदों के झुंड केंद्रीय कक्ष में 'जैल सिंह कांड' पर विचार-विमर्श करने में मुब्तिला थे। ज्यादातर सांसद इस बात को मानते हैं कि धन की पेशकश कोई बड़ी बात नहीं है। अकसर कांटे की टक्करों में धन का खुलकर इस्तेमाल होता है और स्वय जैल सिंह से भी यह बात छिपी नहीं है। जिस समय वीवी गिरि और संजीवा रेड्डी की टक्कर हुई थी, तब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनको सिंडीकेट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीएम सादिक के साथ पार्टी से निकाल दिया था। यह सर्वविदित है कि उस चुनाव में गिरि विजयी हुए थे।

घूस देने का आरोप ? : राजेश पायलट

इस संबंध में जैल सिंह के एक करीबी सूत्र का 'माया' से कहना था, "गुरनाम सिंह के मुख्यमंत्रित्व-काल में सभी अकालियों-हालांकि वे कांग्रेस से नफरत करते थे—ने गिरि को प्रथम वरीयता मत (फर्स्ट प्रिफरेंस वोट) दिया था। इसी तरह उप्र में चौधरी चरण सिंह की बीकेडी के सदस्यों ने गिरि को द्वितीय वरीयता मत दिया था।"

इस सूत्र का कहना है कि जैल सिंह बखूबी जानते हैं कि ये वोट कैसे बटोरे गये। स्वयं संजीवा रेड्डी ने इस बात को कभी नहीं छिपाया कि पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी होते हुए भी उनको कैसे हटाया गया। ज्ञानीजी कोई बच्चे नहीं हैं, वह जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल के पास जितने संसाधन होते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। इसलिए यह कहना कि धन की पेशकश की गयी थी और उसको ज्ञानीजी ने गंभीरता से लिया होगा, विश्वसनीय नहीं लगता।

ऐसा कोई क्यों करेगा ? : वीसी शुक्ल का कहना है कि यदि किसी के पास ४० करोड़ रुपए होंगे, तो वह राष्ट्रपति के बजाय उस पैसे को अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनाने में लगायेगा, जो देश का असली कर्ताधर्ता होता है। शुक्ल का कहना है कि कोई ज्ञानी जी के लिए वोट क्यों खरीदेगा ? यदि किसी को खरीदना ही होगा और यदि खरीद-फरोख्त की गुंजाइश होगी, तो वह प्रति सांसद २५ लाख रुपए खर्च करके १६० सांसदों को खरीद लेगा, ताकि राजीव गांधी से पीछा छूट सके। मोटे तौर पर देखा जाये, तो १६० सांसदों के पाला बदलने के बाद राजीव गांधी की सरकार नहीं टिक सकती। जाहिर

ज्ञानीजी का खेल

या तो वह एक अत्यन्त कुशल अभिनेता और चालाक षड्यंत्रकारी हैं अथवा सठियाये हुए कुंठित व्यक्ति। पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह का इनमें से कोई भी रूप हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों को ही असमंजस में डाल कर चौतरफा संशय उत्पन्न कर दिया है।

१५ मार्च की शाम को वह लगातार यह विश्वास दिलाने की कोशिश में जुटे रहे कि किस प्रकार उन्हें राजनीतिज्ञ और पत्रकार दोस्तों ने धोखा दिया। उनके अनुसार दुबारा राष्ट्रपति-पद का चुनाव लड़ने के लिए ४० करोड़ रु० की पेशकश का उठा विवाद अकस्मात कही गयी बात पर आधारित था, जिसका उपयोग उनके विरोधी जनता की नजर में उन्हें गिराने के लिए कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति इतना सहमे थे कि उन्हे दोस्तों की जेब में छिपे टेप रिकार्डरों का संभावित खतरा नजर आ रहा था।

उनके इस व्यथापूर्ण वक्तव्य के दौरान ही एक टेलीफोन आया। बातचीत के दौरान जैल सिंह यद्यपि यूएनआई शब्द का प्रयोग करते रहे, किंतु अगले दिन की छपी रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि फोन के दूसरी ओर पीटीआई न्यूज एजेंसी थी। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद जब उन्होंने चोगा रखा, तो इसी शिकायत के साथ कि हर कोई उनसे धोखाधड़ी कर रहा है और उनकी जिन्दगी खतरे में डाल रहा है। "आपको मालूम है कि मैं दिल का मरीज हूं," कहते हुए उन्होंने अपना दायां हाथ सीने पर रखा और बोले, "मेरे ऊपर ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं और घबड़ा गया हूं। मैं दिल का मरीज हूं...।"

लगातार वह इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने किसी का नाम लिया है, "मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किंतु यूएनआई ने मुझे बताया है कि प्रीतीश नंदी ने मेरा कोई इंटरव्यू छापा है, जिसमें मैंने चौधरी बलराम जाखड़ (लोकसभाध्यक्ष), वेंकटरमण आदि का नाम लिया है। किंतु मैंने तो कुछ भी नहीं कहा।"

लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने यह माना कि करीब दस दिन पहले वह नंदी से मिले थे, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि नंदी मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगा। मैंने उसके साथ अनौपचारिक और मित्रतापूर्ण बातचीत की थी। उससे मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप समझदार हैं। मैं दिल का मरीज हूं और फिलहाल मुझ पर अत्यधिक दबाव है।"

यह प्रश्न करने पर कि क्या वह कम-से-कम उन लोगों का नाम बतायेंगे, जिन्होंने रुपयों की पेशकश नहीं की? जैल सिंह ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, "उन्होंने रुपए की पेशकश भले ही न की हो, किंतु अधिकांश लोग प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे, बशर्ते मैं राजीव गांधी को बर्खास्त करता। मैंने यह भी नहीं कहा कि मेरे ऊपर किसी ने राजीव को बर्खास्त करने का दबाव डाला। हिंदी में जो मैंने कहा था, उसका आशय यही था कि मुझे उकसाया और प्रोत्साहित किया जा रहा था।"

जैल सिंह चौधरी बलराम का नाम आने के कारण अत्यधिक चिंतित थे। "मैंने उनका अथवा किसी और का रुपयों की पेशकश के सिलसिले में कतई नाम नहीं लिया था। किंतु सभी प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित थे।"

जैल सिंह इस समाचार से भी व्यग्र थे कि नंदी के साथ हुई उनकी बातचीत 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में छप गयी है। मगर उन्होंने माना, "मेरी बेवकूफी थी जो मैंने 'संडे' को इंटरव्यू दिया। मगर कहा मैंने कुछ और था।" नंदी पर उन्होंने बहरहाल गद्दारी का आरोप लगाया।

उनका दावा है कि उन्होंने मित्रमंडली में हुई आकस्मिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने या न लेने की सलाह की चर्चा की थी, जिसे मेरा प्रामाणिक बयान बताया गया है।

उनके अनुसार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 'मेरे कुछ मित्र चाहते थे कि मैं नामांकनपत्र दाखिल करूं, चाहे उसके कारण राजीव के उम्मीदवार से ही टक्कर क्यों न लेनी पड़े। वी वी गिरि ने भी अधीकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता था।' जैल सिंह के यह कहने पर कि खर्च-वर्च कहां से आयेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मित्रों ने यह विश्वास दिलाया था कि पैसे की कोई चिन्ता नहीं। कुछ ने ध्यान दिलाया था कि जब गिरि आधिकारिक उम्मीदवार के विरोध में खड़े हुए थे, तो उनके सिर पर खुद प्रधानमंत्री का हाथ था। यदि जैल सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री की ताकत और साधनों का मुकाबला करना पड़ेगा। तब जो लोग उनके चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, उन्होंने कहा, "हम भी करोड़ों खर्च कर सकते हैं। ३०-४० करोड़ रु० तक कोई मुश्किल नहीं है। किंतु दुविधाग्रस्त मित्रों ने कहा कि शासक दल तो इससे कहीं अधिक धन-शक्ति लगा सकता है। इस प्रकार न तो कभी किसी ने पक्के तौर पर कोई निश्चित रकम की पेशकश की न किसी ने मांग की। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो गया? कुछ लोग नहीं चाहते कि मुझे नेकनामी मिले। वे मेरी विश्वसनीयता को खतम कर देना चाहते हैं। कारण उन्हें भय है कि मैं कहीं कुछ ऐसा न कह बैठूं, जिससे राजीव की पार्टी का विनाश हो जाये।"

उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका ऐसा बुरा चाहने वाले कौन लोग हैं? यह जोर देने पर कि वह कम-से-कम 'टाइम्स आफ इंडिया' में सुभाष किरपेकर द्वारा प्रकाशित नामों—नरसिम्हाराव, शिवशंकर, अर्जुन सिंह व भजनलाल— को स्वीकारें या नकारें। जैल सिंह इसका कोई जवाब न देने के लिए लगातार बगलें झांकते रहे। उनकी ओर से इस संशय और ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करने की कोई इच्छा नजर नहीं आयी। विवाद बरकरार रहे, यही उनका मंशा जान प्रड़ता है। यद्यपि उन्होंने इस बात को पुन: दोहराया कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने पर तुले हैं, इसीलिए ४० करोड़ की पेशंकश के मसले को तो उछाल रहे हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरंदाज कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं और वे किनके लिए महत्वपूर्ण हैं? जैल सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यद्यपि राजीव गांधी की चर्चा चलने पर उनकी खामोशी कुछ और गहरी थी और पंजाब पर तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हां, यह जरूर है कि प्रधानमंत्री बनने के कौन इच्छुक थे, इस पर ज्ञानीजी की निश्चित उत्तर देने की उत्सुकता पुन: बढ़ गयी। उनमें से अधिकांश नाम वही हैं, जिनका कि उल्लेख रुपयों की पेशकश के लिए किया जा रहा है। रहस्यमयी मुस्कान के साथ ज्ञानी ने कहा, "उचित समय आने दो।" क्या उस समय नाम बतायेंगे? उत्तर में पुन: जो मुस्कराहट मिली, उसके पीछे यह संकेत था कि नाम से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि उनकी पहचान वह किसे बतायेंगे प्रधानमंत्री को या उनके विरोधियों को। तब तक जैल सिंह आराम से अपने बगीचे में शांति से फूल पौधों की निराई-गोड़ाई करेंगे। ■

कुछ यक्ष प्रश्न

१—क्या वह व्यक्ति राजेश पायलट थे, जिन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को इस बात के लिए रिश्वत देने की पेशकश की थी कि वह ४० करोड़ के मामले में वीपी सिंह, अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल और आरिफ मोहम्मद खान का नाम ले दें? ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानीजी ने भेंटकर्ताओं को पायलट का नाम भी दिया था, लेकिन यह उनकी मरजी पर छोड़ दिया था कि वे उनका नाम छापे या नहीं।

२—क्या इस ताजा रहस्योद्घाटन में जैल सिंह ने राजीव को बचाने की कोशिश की है? क्योंकि प्रीतीश नदी (इलंस्ट्रेटेड वीकली) और रजत शर्मा (आनलुकर) को दिये साक्षात्कार में ज्ञानी जैल सिंह का कहना है, "मेरे साथ दुर्भाग्यवश यह शरारत (जनमोर्चा-नेताओं को फंसाने का प्रस्ताव) राजीव के द्वारा नहीं, बल्कि उनके आदमियों के द्वारा हुई है। मैंने राजीव को बर्खास्त नहीं किया, फिर इस बारे में विवाद क्यों?

३—क्या मनिराम बागड़ी (हरियाणा के राजनेता) वास्तव में बलराम जाखड़ के समर्थन में सांसदों की सूची लेकर उनके पास गये थे?

कहा जाता है कि इस सबसे बागड़ी बहुत खफा हैं और उन्होंने इस तरह के आरोप लगानेवालों को देख लेने की धमकी दी है। लेकिन ज्यादातर सांसदों का कहना है कि उन्होंने बागड़ी को जाखड़ के कार्यालय का चक्कर लगाते हुए देखा है। कहा तो यहां तक जाता है कि बागड़ी वेस्टर्न कोर्ट (नयी दिल्ली) के जिस कमरे में रह रहे हैं, वह बलराम जाखड़ के लिए आरक्षित है।

४—क्या खरगोन (मध्य प्रदेश) के सांसद सुभाष यादव ज्ञानीजी से मिले थे और उन्हें अर्जुन सिंह का संदेश तथा सांसदों की सूची सौंपी थी?

यादव अर्जुन सिंह के विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने दृढ़ता से औपचारिक तौर पर इस आरोप का खण्डन किया है। यह भी सच है कि कांग्रेस-इ पार्टी में ही भारी संख्या में अर्जुन सिंह-विरोधी मौजूद हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री की नजरों से गिराने का षड्यंत्र कर सकते थे।

■

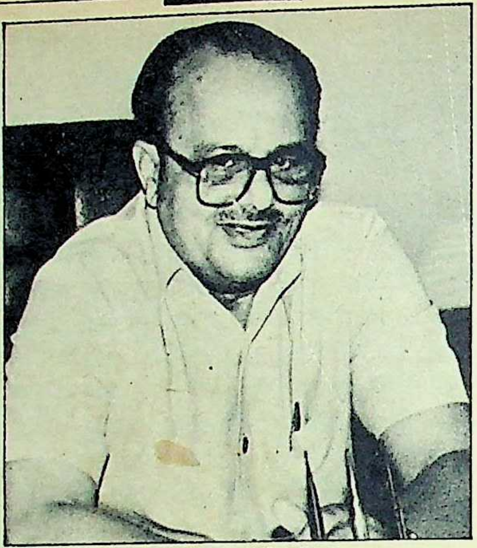
ज्ञानीजी का एक शिकार: अर्जुन सिंह

है, कोई भी व्यक्ति पहले ज्ञानीजी को जितवाकर फिर राजीव को गिराने का टेढ़ा रास्ता क्यों अख्तियार करेगा? इसलिए यदि किसी ने इस धन का जिक्र किया भी था, तो वह मात्र एक चालू आश्वासन था, जिससे ज्ञानीजी लड़ने के लिए उत्साहित हो जायें। इसके अलावा शायद ही ज्ञानीजी पर कोई ऐसा दांव लगाता, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बंदरभभकी तो काफी दी, लेकिन किया कुछ नहीं और हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता था।

इसी बात की पुष्टि एआईसीसी के पूर्व महामंत्री जितेंद्र प्रसाद भी करते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति पद के बंधन से बंधे ज्ञानीजी जो काम नहीं कर सके, उसे वह अब अंजाम देना चाहते हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी को हटाने या विभाग बदलने के लिए राजीव गांधी को किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत है। खासकर ज्ञानीजी की तो बिलकुल नहीं, ज़िन्होंने राजीवजी को बदनाम करने और सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की थी।"

मौका और जरिया: यदि प्रसाद का कहना सही है, तब ज्ञानीजी बहुत चतुर हैं। इससे यह भी पता चलता है कि एक ख़ास समय, एक खास पत्रिका के जरिये उन्होंने यह गोला दागा है। 'संडे' के जरिये बोलने से किसी को यह शक नहीं हो सकता था कि ज्ञानीजी अपने दोस्त और दिल्ली दरबार के विरोधी कुलदीप नायर और सतिंदर सिंह द्वारा सिखाये-पढ़ाये गये हैं। ज्ञानीजी ने मौका भी अच्छा चुना था। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हेरफेर हुआ है और राज्यों में भी नेतृत्व बदला है। ऐसे मौकों पर निराश लोगों की संख्या बढ़ जाती है। जो लोग सत्ता पाने की फिराक में बैठे होते हैं, वे वंचित रहने पर नेतृत्व का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है, ज्ञानीजी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अर्जुन सिंह की वफादारी संदिग्ध बनाने के पीछे भी यह उद्देश्य हो सकता है कि मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में इंका की स्थिति डांवाडोल हो। नरसिम्हाराव एक अच्छे मंत्री ही नहीं, एक संजीदा सलाहकार भी हैं। उनको संदेह के घेरे में लाने के पीछे कैबिनेट की सहज गतिविधियों को झटका पहुंचाना और प्रधानमंत्री को एक विश्वसनीय सलाहकार से वंचित करने का इरादा हो सकता है। इसके अलावा यदि नरसिम्हाराव को हटाया जाता है या उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, तो राजीव गांधी ने हाल के फेरबदल के जरिये जो सत्ता का संतुलन बिठाया है, वह गड़बड़ा सकता है। यह भी गौरतलब है कि हटाये गये मंत्री और उपेक्षित सांसद नियराते चुनावों को देखकर भूतपूर्व कांग्रेसियों के टोले के पास मंडरा सकते हैं।

सर्वाधिक नाजुक मसला: सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रपति और लोकसभाध्यक्ष को लेकर है। अभी तक बलराम जाखड़ पर विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि वह विपक्ष की आवाज कुचलते रहते हैं और ऐसा मुद्दा उठाने नहीं देते, जिससे राजीव गांधी परेशानी में पड़ें। जैल सिंह ने कहा है कि जाखड़-समर्थक सांसदों की सूची मनीराम बागड़ी लेकर आये थे। ऊपर से देखने पर यह बात विश्वसनीय लग सकती है। जब ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय श्री जाखड़ उनके मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और बाद में उपमंत्री भी बना दिये गये थे। बागड़ी श्री जाखड़ के करीब माने जाते थे। इस प्रकार ज्ञानीजी ने श्री जाखड़ के बारे में जो संदेह पैदा किया है, उसे आसानी से हटाना संभव नहीं— और यही स्थिति राष्ट्रपति वेंकटरमण की है।

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध श्रीलंका समझौते के बाद से तनावग्रस्त हैं। केंद्र की तमिलनाडु राजनीति से भी राष्ट्रपति वेंकटरमण प्रसन्न नहीं हैं। वह मूपनार और चिदंबरम को भी पसंद नहीं करते, जबकि दोनों राजीव गांधी के खास आदमी हैं। राजीव गांधी होली खेलने वेंकटरमण और जैल सिंह के यहां पहुंचे थे, लेकिन इससे तनाव शिथिल हुआ है, ऐसा नहीं माना जाता।

सलाहकारों की चिंता: राजीव गांधी के सलाहकार चिंतित हैं कि यदि आगामी चुनावों में राजीव गांधी को सामान्य बहुमत प्राप्त होता है, तो वेंकटरमण का रुख क्या होगा? ज्ञानी जैल सिंह ने संदेह का जो माहौल पैदा कर दिया है, उससे बहुत संभव है, चुनावों को समय से पहले कराने का विचार शिथिल पड़ जाये, क्योंकि भले ही आगे चलकर वेंकटरमण का रवैया बहुत अनुकूल ही रहे, राजीव गांधी अब उन पर पूरी तरह भरोसा करने से हिचकिचायेंगे। (देखें बाक्स)

ज्ञानीजी ने राजीव गांधी के साथियों की महत्वाकांक्षाओं को भले ही स्वेच्छा से या प्रधानमंत्री खेमे के इशारे पर उजागर किया हो, लेकिन इससे यह आम धारणा बन गयी है कि बजट सत्र के बाद राजीव गांधी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल कर सकते हैं तथा विश्वासपात्र समझे जाने वाले कुछ मंत्रियों को हटाकर राजनीति के पुराने खिलाड़ी जगन्नाथ मिश्र, लोकपति त्रिपाठी और माधव सिंह सोलंकी जैसे अविश्वसनीय और परेशानी पैदा करने वाले लोगों को विश्वासपात्रों की

पांत में बिठा सकते हैं। राजीव गांधी इस कसरत का जायजा लेना पसंद करेंगे कि सत्ता से बाहर कर देने के बाद विश्वासपात्रों और सत्ता में शामिल करने के बाद विरोधी और अविश्वसनीय तत्वों का आचरण कैसा रहता है। यदि कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रहती है, तो कांग्रेस-इ के एक अखिल भारतीय महासचिव की मान्यता है कि सर्दियों में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। देखना यह है कि ज्ञानीजी ने कांग्रेस-इ के चोटी के नेताओं के बीच परस्पर संदेह का जो वातावरण पैदा कर दिया है, वह चुनाव परिणामों और कांग्रेस-इ पार्टी की एकता को किस सीमा तक प्रभावित करेगा।

हिंदी भाषी क्षेत्र के चार वरिष्ठ सांसद जैल सिंह के साक्षात्कार के प्रकाशित होने के बाद अशोक होटल में रात्रि भोज पर मिले। इन सांसदों को राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे हुए हैं। पार्टी में चल रही गुटबाजी को समाप्त करने के सिलसिले में विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र ये सांसद बहुत आशावान नहीं हैं। संयोग से उसी कक्ष के ऊपरी तल पर गृहमंत्री बूटा सिंह भी एक सरकारी भोज में शिरकत कर रहे थे। जैसे ही इन चारों सांसदों को पता चला कि बूटा सिंह भी इसी होटल में हैं, वे शीघ्रतापूर्वक वहां से चले गये। इन सांसदों की मान्यता है कि श्री जाखड़ से नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर आश्रित हैं। ऐसी ही स्थिति नरसिम्हाराव की भी है जो अपने

किसने क्या कहा ?

श्री जैल सिंह द्वारा 'संडे' को दिये गये साक्षात्कार ने कई बुनियादी सवाल उठाये हैं और चंद पुराने संदेहों की पुष्टि की है। दुख की बात है कि उनके द्वारा उठाये कई महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीति में धन शक्ति की भूमिका को लेकर उठे पाखंड पूर्ण विरोधी स्वरों में दब गये हैं। यह कोई नयी खबर नहीं है कि चुनावों में अंधाधुंध पैसा बहाया जाता है अथवा कांग्रेसी जहाज को छोड़ने के लिए उसके चूहे उसे डुबोने में भी हिचकिचायेंगे नहीं। यह भी कोई नयीं बात नहीं कि राजनीतिज्ञों और उनके मित्रों के पास बेहिसाब काली कमाई है, जिसका इस्तेमाल वे सत्ता हथियाने या उससे सही-गलत तरीके से चिपके रहने के लिए करते हैं।—**एस० सहाय**

राजनीति में काले धन की भूमिका कोई नयी घटना नहीं है। ताजा-तरीन उदाहरण नागालैंड का है, जहां विधानसभा-चुनावों में वोट पाने के लिए कांग्रेस-इ द्वारा भारी मात्रा में धन खर्च किया गया। इसी प्रकार तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक गुट द्वारा विधायकों की खरीद के लिए नोटों का सहारा लेने की भी खबर थी। किंतु सबसे शर्मनाक बात यह होगी कि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव के दौरान इस लेनदेन की प्रक्रिया को अपनाया गया...जैल सिंह को या तो मुंह बंद रखना चाहिए था या पूरा खुलासा करना चाहिए था।—**द स्टेट्समैन**

यह स्पष्ट है कि ज्ञानी जैल सिंह अपने कथनों द्वारा उठे संदेहों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। वह जानबूझकर ऐसे मामले को रहस्यमय बना रहे हैं, जो पूरी तरह उजागर है। कभी वह कहते हैं कि हम पंजाबी जब करोड़ की बात करते हैं, तो उसका मतलब लाख होता है। दूसरे पल ही वह कहते हैं कि उनका इशारा पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की ओर नहीं, वर्तमान मंत्रियों की ओर है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी व लोकसभा अध्यक्ष श्री जाखड़ जानबूझकर ज्ञानी के बिछाये जाल में फंस गये। यदि वे नादानी का परिचय देते है, तो ज्ञानी उसका भरपूर मजा क्यों न उठायें।—**मधुलिमये**

हमारे सांसदों की दिलचस्पी केवल इसी बात में रही है कि उन्हें जैल सिंह को ३० से ४० करोड़ रुपए का वायदा करनेवालों के नामों की जानकारी हो। उनको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आयी कि धन-शक्ति अब देश के सर्वोच्च पद के चुनावों में भी उपयोग की जाने लगी है। देश की राजनीति आज जिस निम्न स्तर पर उतर आयी है, वह एक गंभीर चेतावनी है।—**एस मुलगांवकर**

ज्ञानी जैल सिंह के साक्षात्कार की रोशनी में संवैधानिक प्रक्रिया में भितरघात करने की कोशिश करनेवाले लाजिमी तौर पर जवाबदेह हैं, चाहे वे गैरकम्युनिस्ट विपक्ष के हों, प्रेस के हों अथवा स्वामी-गुरु या अंतरराष्ट्रीय दलाल ही क्यों न हों। राष्ट्र अब भली-भांति जान गया हैं कि 'उच्च पदों में व्याप्त भ्रष्टाचार' के खिलाफ जबर्दस्त युद्ध छेड़ने के पीछे क्या घिनौनी साजिश थी। इस अर्थ में ज्ञानीजी का 'संडे' को स्वेच्छा से दिया गया साक्षात्कार, एक सार्थक भूमिका निभा सकता है।—**द टाइम्स आफ इंडिया**

जब से संसद में इस विवाद का विस्फोट हुआ है, ज्ञानीजी मिलने-जुलनेवालों से कहते हैं कि उनकी टिप्पणी 'आकस्मिक' थी... वह दुबारा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए यह 'पेशकश' अमली रूप नहीं ले सकी। किंतु अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह भी संकेत देते रहे हैं कि यह पेशकश कांग्रेस-इ की ओर से पर्याप्त वोटों और धन-दोनों ही रूपों में आयी थी और वे लोग अभी कांग्रेस में मौजूद होने के साथ 'वफादार' और सरकार व पार्टी के उच्च पदों पर आसीन हैं। —**इंडियन एक्सप्रेस**

वह (ज्ञानीजी) दो-टूक तरीके से इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह ऐसे अनेक कांग्रेस-इ सांसदों को जानते हैं जो आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ उन्हें वोट देते और उन्हें उन लोगों का भी पता था जो उनके दुबारा चुने जाने के लिए धन खर्च करते। ऐसी स्थिति में जैल सिंह के लिए पार्टी से बाहर आनेवालों व धन से जोड़-तोड़ करनेवालों का नाम बताने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। धन-शक्ति से सांसदों-विधायकों को प्रभावित करना भ्रष्टाचार है और जैल सिंह कहते हैं कि उन पर राजीव गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करने का दबाव था। ऐसी स्थिति में इस संभावित भ्रष्ट सौदेबाजी में लिप्त होने के आरोप के सिलसिले में खुद के पाक-साफ होने की सफाई देना, उनके लिए नैतिक रूप से जरूरी है।—**द हिंदुस्तान टाइम्स**

ज्ञानीजी के साक्षात्कार के प्रकाशन का समय, लोकसभा में इस मामले को उठाने का नाटकीय ढंग, प्रधानमंत्री द्वारा जांच कराने का हड़बड़ी में किया गया वादा और इससे भी ज्यादा नाटकीय ज्ञानीजी को चुनाव न लड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया चाटुकारिता पूर्ण धन्यवाद। यह सब एक ही शृंखला की कड़ियां थीं और इससे जाहिर होता था कि यह प्रकरण कांग्रेस-इ के प्रतिद्वंद्वियों, खासकर वीपी सिंह और अरुण नेहरू का प्रभाव घटाने की कोशिश थी। यह बात मुश्किल से ही गले उतर सकती थी कि राजीव के उम्मीदवार के खिलाफ जैल सिंह को खड़ा करने के लिए वीपी सिंह और उनके साथियों द्वारा धन की पेशकश किये जाने का षड्यंत्र रचा गया।

बहरहाल, राजीव खेमे में यह उल्लास ज्यादा देर नहीं टिका। निश्चित रूप से उन्हें इस धोखे की जानकारी नहीं थी जो जैलसिंह करने वाले थे। पहला साक्षात्कार देने के हफ्ते भर बाद ही उन्होंने दूसरा साक्षात्कार दे डाला। इस साक्षात्कार में उन्होंने राजीव द्वारा किये गये जांच के वायदे की खिल्ली तो उड़ायी ही, साथ ही यह भी कहा कि उन्हें धन देने की पेशकश करने वालों में से कुछ अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब हमला करने की बारी विपक्ष की थी। पहले राजीव गांधी ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति चुनाव में उसने भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब यह आरोप लगाने का अधिकार विपक्ष के पास है।

—'द टेलीग्राफ' में निखिल चक्रवर्ती

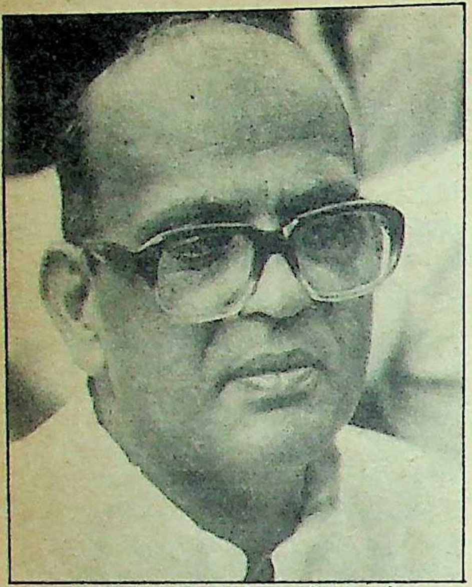

ज्ञानीजी के विवाद की सीधी मार से बच गये : वीपी सिंह

राजीव गांधी की चिंता का विषय ४० करोड़ रुपए का मामला नहीं, बल्कि ज्ञानीजी द्वारा पैदा किया गया संदेह का वातावरण है जो आम चुनावों में पार्टी में आतंरिक फूट का वायस बन सकता है!

ज्ञानीजी पर दांव कोई क्यों लगायेगा ? : वीसी शुक्ल

गृह प्रदेश आंध्र में ही चुनाव हार गये थे और जिन्हें महाराष्ट्र से चुनाव जिताकर संसद में लाया गया था। पी० शिवशंकर की भी उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि वह भी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेतृव की कृपा से पिछले दरवाजे से राज्यसभा में आये हैं। एकमात्र अर्जुन सिह ही ऐसे है जो राजीव गांधी के लिए अपरिहार्य हैं और जिनके बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस-इ का बंटाढार हो सकता है।

हाल ही मंत्री बनाये गये एक युवा सासद भी राजीव गांधी की परेशानी का कारण बन गये हैं। ज्ञानी जैल सिंह का कहना था कि इसी सांसद ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की स्थिति में उनका समर्थन करनेवाले सौ सांसदों की सूची उन्हें दी थी। यदि इस सांसद को पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, तो वह विपक्ष में शामिल हो सकता है और अपने गृह प्रदेश के कुछ दिग्गज कांग्रेस-इ नेताओं को भी फोड़ सकता है। अतः राजीव गांधी की चिता का विषय ४० करोड़ रुपए का मामला नही, बल्कि ज्ञानीजी द्वारा पैदा किया गया संदेह का वातावरण है जो आम चुनावों में पार्टी में आतरिक फूट का वायस बन सकता है।

ज्ञानीजी से निपटने की सलाह : राजीव गांधी के एक चहेते संपादक की सलाह है कि ज्ञानीजी और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अत: उनकी साख को चुनावों के पूर्व ही मटियामेट कर देना जरूरी है अन्यथा वह और भी घातक कदम उठा सकते हैं। इससे पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में गहरा वैमनस्य पैदा हो जायेगा जो चुनावों मे विजय हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

कांग्रेस-इ के एक पुराने घाघ नेता ने अपना नाम गुप्त रखने का आग्रह करते हुए प्रवचन शैली में कहा, "समझ लीजिए, ज्ञानीजी जैसे अपने स्थापित विरोधियों द्वारा पैदा किये गये संदेह की वजह से राजीव गाधी, एनडी० तिवारी, नरसिम्हाराव, अर्जुन सिह, हरिदेव जोशी, दादा, शरद पवार और जगन्नाथ मिश्र को घोर निराशा की ओर ले जा रहे हैं।" इसी नेता का यह भी कहना है कि युवा पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का मजाक उड़ाने की आदत होती है, क्योंकि वे उन्हें उपेक्षा के योग्य मानते हैं। वृद्ध ज्ञानीजी के साथ राजीव गांधी को जो कटु अनुभव हुए हैं, उसके कारण उन्होंने और उनके युवा साथियों ने भारतीय राजनीति के धोतीधारी इन नेताओं के महत्व को नहीं समझा, तो इससे ज्ञानीजी को ही अपने उस इरादे को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिसे वह साक्षात्कारों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। यह इरादा है, कांग्रेसियों को भूतपूर्व कांग्रेसियों की शरण में ले जाना, भले ही वे ऐसा अपने आप करें या स्वयं राजीव गांधी हल्ला करके उन्हें ऐसा करने के लिए मज़बूर कर दें। ज्ञानीजी ने एक बार कहा था, "दुश्मन की जमीन में संदेह का बीज बो दीजिए और फिर उसकी तबाही का तमाशा देखिए।" क्या ज्ञानीजी यही चाल चल रहे हैं।

—विजय दत्त, [illegible] सरकार के साथ

जब वेंकटरमण प्रधानमंत्री बने ?

दिल्ली के झक्की राजनेता भी इस बात पर विस्मित है कि राष्ट्रपति वेंकटरमण जैसे सीधे-सादे व्यक्ति भी हताशा में ऐसी मनःस्थिति में पहुंच जायेंगे कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव आये, तो वह उस पर विचार करेंगे। लेकिन यह बेतुका किस्सा जोरों पर फैला है और जो इस में शामिल थे, वे इसकी सत्यता के प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन जिस समय ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री के बीच शीत युद्ध शिखर पर था, उस वक्त कुछ भी होना मुमकिन था।

इस सिलसिले में जार्ज फर्नांडीस, उपराष्ट्रपति वेंकटरमण से दिल्ली के मौलाना आजाद रोड स्थित उनके निवास पर मुलाकात करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे या प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी के समय संवैधानिक संकट से उत्पन्न शून्य को वेंकटरमण द्वारा भरने की सभावना पर चर्चा की थी। मामला तब और गंभीर हो गया था, जब कुछ सांसद वेंकटरमण के पास प्रस्ताव ले कर पहुंचे। उनसे मिलनेवालों में विद्याचरण शुक्ल और आरिफ मोहम्मद खान भी थे। विद्याचरण उस समय कांग्रेस-इ में ही थे।

वेंकटरमण से मिलनेवाले एक व्यक्ति एक रोचक संस्मरण सुनाते हैं जो जैल सिह द्वारा राजीव गांधी को हटाकर वेंकटरमण को प्रधानमंत्री बनाने की संभावना की पुष्टि करता है। उन्होंने बताया, "पूर्व निर्धारित मुलाकात के तहत मैं उनसे मिलने गया। मुझे बैठक में बिठाया गया। लगभग पांच मिनट बाद वह आये और एक विदा लेते व्यक्ति की तरह बातें करने लगे।" बताया जाता है कि वेंकटरमण ने कहा था कि उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और मद्रास लौटने की तैयारी में हैं।

विवाद का सर्वाधिक नाजुक पक्ष: राष्ट्रपति वेंकटरमण

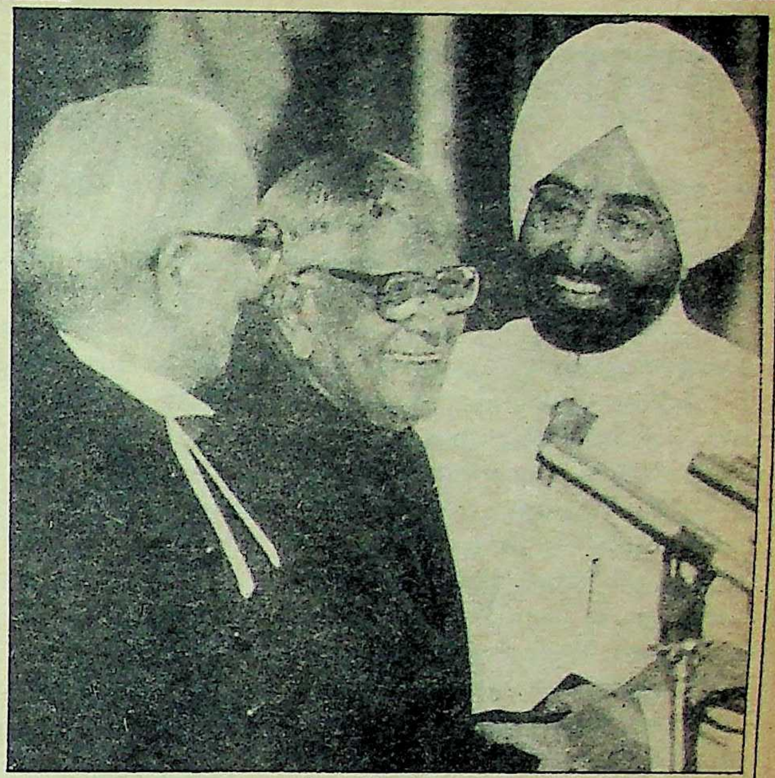

यदि प्रत्याशी न बनाया जाता, तो...: वेंकटरमण और ज्ञानी जैल सिंह

वेंकटरमण के ऐसा कहने पर उक्त भेंटकर्ता ने उन्हें राजीव गांधी और ज्ञानीजी के बीच चल रहे तनाव का हवाला दिया। भेंटकर्ता के अनुसार, "मैंने कहा कि ज्ञानीजी राजीव गांधी को बर्खास्त करने के लिए करीब-करीब तैयार हैं।"

वेंकटरमण जानना चाहते थे कि क्या यह संवैधानिक रूप से संभव है? तब मैंने कहा, "ज्ञानीजी ने अशोक सेन सहित कई विधिवेत्ताओं से सलाह ले ली है।" भेंटकर्ता के अनुसार, "इसी समय मैंने इशारा किया कि ज्ञानीजी की इच्छा आपको प्रधानमंत्री मनोनीत करके अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने की है। आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते।" बताया जाता है कि उस वक्त वेंकटरमण ने इस मामले में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी।

वेंकटरमण ने मुलाकात के लिए ज्ञानीजी से टेलीफोन पर बात की और दो दिन बाद मिलना तय हो गया। उसके पूर्व ही उक्त भेंटकर्ता ने ज्ञानीजी को वेंकटरमण से हुई अपनी बातचीत से अवगत करा दिया था। लेकिन इस मुलाकात के पहले ही ज्ञानीजी को राजीव गांधी द्वारा भोज का निमंत्रण मिला और ज्ञानीजी असमंजस में पड़ गये। नतीजतन उस दिन यह मुलाकात नहीं हो सकी। उक्त भेंटकर्ता की ज्ञानीजी से फिर टेलीफोन पर बात हुई और ज्ञानीजी ने अपनी अस्वस्थता का हवाला देते हुए अगले दिन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिये। इस प्रकार एक दिन बाद ज्ञानीजी और वेंकटरमण की मुलाकात हुई। यह सच है कि उस दिन दोनों के बीच किसी विषय पर विचार-विमर्श नहीं हुआ। ज्ञानीजी ने बाद में कहा था, "मैं अस्वस्थ था, वह मुझे देखने आये, लेकिन उस विषय पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। असलियत यह है कि जैसे ही यह खबर बाहर आयी कि वह (वेंकटरमण) असंतुष्टों से मिल रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश कर दी गयी और वेंकटरमण का मामला यहीं समाप्त हो गया।"

उक्त भेंटकर्ता ने इस बात की पुष्टि की कि ज्ञानीजी और वेंकटरमण दोनों ने बताया था कि इस विषय पर उस दिन उनकी बातचीत नहीं हुई थी। भेंटकर्ता के अनुसार, "मैंने वेंकटरमण से कहा कि ज्ञानीजी चाहते थे कि इस बारे में पहल आपकी ओर से हो। उस समय वेंकटरमण ने यह जायजा लेने की इच्छा जाहिर की थी कि क्या ज्ञानीजी के लिए संवैधानिक रूप से राजीव गांधी को बर्खास्त करना या पद से हटने के लिए कहना संभव है?

उक्त भेंटकर्ता ने उनसे वादा किया कि अशोक सेन का रुख जानने के लिए वह उन्हें उनके पास लायेगा और समय तथा तारीख तय हो गयी। इस बैठक के पहले ही प्रधानमंत्री के जासूसों, जिनमें राजेश पायलट भी शामिल हैं, ने वेंकटरमण को बुलाकर बताया कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद वेंकटरमण ने भेंटकर्ता को फोन पर कह दिया कि इस मामले में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

यह एक अपवाद है कि कांग्रेस पार्टी ने वेंकटरमण को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा नामांकन भरने के केवल पंद्रह दिन पहले की। आम तौर पर प्रत्याशी की घोषणा एक-दो दिन पहले की जाती है। वास्तव में वेंकटरमण को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाये जाने के पहले इस समय के जनमोर्चा-नेताओं ने राजीव के प्रत्याशी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की थी। इसका श्रेय, विद्याचरण शुक्ल को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वेंकटरमण से भेंट की। इसी मुलाकात के बाद राजीव-खेमे में हलचल मची और उसने शंकरानंद को उम्मीदवार बनाने का विचार त्याग दिया। यह भी कहा जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी वेंकटरमण से भेंट की थी, मगर जिन्हें सचाई पता है, वे जानते हैं कि यह एक औपचारिक भेंट थी। वेंकटरमण जैसे वरिष्ठ राजनेता को उनके जैसा कनिष्ठ आदमी सलाह नहीं दे सकता।

वैसे जो सचाई उभरकर सामने आती है, उससे यही लगता है कि वेंकटरमण राजीव के विरोध में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता की हैसियत से इस बुजुर्ग नेता का यह महसूस करना जायज था कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी दल उनको अनदेखा कर रहा है। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हुई, तो जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं, "हम सबने राहत की सांस ली।"

एक कांग्रेसी के रूप में वेंकटरमण सिद्धांतों के पक्के होने के लिए विख्यात हैं। आपातकाल के दौरान वह 'स्वराज' के संपादक थे। उन दिनों उन्होंने जेल जाने की परवाह न करते हुए आपातकाल और मूलभूत अधिकारों के हनन का विरोध किया था।

वेंकटरमण को राष्ट्रपति बनाये जाने का सभी ने स्वागत किया था, सिवाय राजीव गांधी के कुछ अति विश्वसनीय साथियों के। बहरहाल सचाई यह है कि आपातकाल के दौरान वेंकटरमण ने श्रीमती गांधी का नहीं, उनकी नीतियों का विरोध किया था। वह अब राजीव गांधी के शासन करने की तानाशाही पद्धति का भी विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह राजीव गांधी का विरोध करेंगे। यद्यपि राजीव गांधी के साथियों ने देशभक्ति को व्यक्ति पूजा से जोड़ दिया है—इसीलिए कहा जाता है कि राजीव को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ■

ज्ञानीजी की योजना यह थी?

क्या ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसी योजना बनायी थी, जिसके तहत या तो वह दुबारा राष्ट्रपति बन जाते या फिर ऐसे व्यक्ति के सेहरा बांधते जो राजीव गांधी की रबर मोहर न बन सके।

सिलसिला शुरू हुआ कुख्यात खतों से। ये खत थे, तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम। इनके लेखक बताये गये फेयर फैक्स एजेंसी वर्जीनिया के जार्ज गोर्डन मैक से लेकर इंडियन एक्सप्रेस के एस० गुरुमूर्ति तक। इसका फौरी नतीजा हुआ आर०एन० गोयनका के दिल्ली की सुन्दर नगर स्थित कोठी पर सरकार का छापा। इससे राष्ट्रीय प्रेस में तूफान पैदा हो गया। विपक्ष को राजीव-अमिताभ और अंबानी पर धोखाधड़ी का इलजाम लगाने का मौका मिला। इसी छापे के दौरान संयोग से जैल सिह द्वारा राजीव गांधी को लिखा गया पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में विश्वासपूर्वक कोई नहीं कह सकता कि यह एक जान बूझकर की गयी भूल थी या सीबीआई अधिकारियों तक पहुंचने की एक चाल थी। दरअसल राजीव को जो पत्र भेजा गया था, वह सुंदर नगर की कोठी में मिले पत्र से अलग था। कहा जाता है कि जब जांच-पड़ताल जारी थी, तो चन्द्रा स्वामी अपने सलाहकार और मार्गदर्शक कैलाश नाथ अग्रवाल के ग्रेटर कैलाश पार्ट-२ स्थित मकान में थे और लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि छापा मारने वाली पार्टी को कुछ मिला या नहीं। कुछ लोग अब यह कह रहे हैं कि राजीव के सलाहकार अपने ही बिछाये जाल में फंस गये। इससे गोयनका को हो-हल्ला मचाने का सुनहरा मौका मिल गया। साथ ही जैल सिह के पिछली ९ मार्च के पत्र में लगाये गये आरोपों को प्रचंड प्रचार मिला, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया था और जो सीआईबी अफसरों को मिले मसौदे से अलग था।

यह उजागर सचाई साबित करती है कि जैल सिह को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बारे में गोयनका, गुरुमूर्ति ने जो सलाह दी थी, उसमें उनकी (ज्ञानीजी) कोई दिलचस्पी नहीं थी। पत्र को जैल सिह द्वारा लिखाये गये मसौदे के आधार पर जोगिंदर सिंह ने तैयार किया था। संवैधानिक सलाह ए०जी० नूरानी से ली गयी थी। बाद में राष्ट्रपति के सचिव वर्धन ने उसे देखा-ठीक किया था। राष्ट्रपति की बात से शायद गुरुमूर्ति को ऐसा लगा था कि पत्र को उनकी सलाह के बाद भेजा जायेगा, पर इस पर अमल नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि जैल सिंह को अपने पुराने मित्रों-सलाहकारों पर विपक्षी नेताओं से ज्यादा भरोसा था, जिन्हें वह सुख के दिनों का ही साथी समझते हैं।

चंद्रा स्वामी का प्रवेश : राजीव गांधी की जैल सिह, गोयनका, वाडिया और वीपीसिंह को एक ही झटके में खत्म करने की रणनीति ने ज्ञानी को खूब बढ़ाया-चढाया और जनता की सहानुभूति प्रदान की। दरअसल राजीव गांधी की इस गलती के बाद उनकी विश्वसनीयता में आयी गिरावट से उनकी अपनी ही पार्टी के सदस्यों को उनके पतन का भय हो गया था। हरियाणा की अभूतपूर्व पराजय ने इस भय को और मजबूत किया और कांग्रेसियों को जैल सिह में संभावित बदले का भूत नजर आने लगा, क्योंकि ज्ञानी तब तक जनता की निगाह में शहीद बन चुके थे। चन्द्रा स्वामी को राजीव गांधी के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध की गंध मिली। वह संभावित विजेता का प्रियपात्र बनने के सपने सजोये उसमें कूद पडे। समझा जाता है कि उन्होंने 'अनेक सांसदों और अन्य सूत्रों' को जानकारी दी थी कि अगर जैल सिह की विजय के लिए कुछ वोट भी खरीदने पडे, तो पैसे की किल्लत नहीं होगी। बदले में जैल सिह राजीव को बर्खास्त कर देंगे या उन पर अभियोग लगायेंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। चन्द्रा स्वामी की राष्ट्रपति-पद के लिए पसंद थे—पीवी नरसिम्हा राव। यही एक चूक हो गयी। यह अफवाह फैल गयी कि नरसिम्हा राव ने जैल सिह का पत्र लिखने में मदद की है और मामाजी श्रीमती सोनिया गांधी के पिता की वसीयत की एक प्रति लाये हैं, जिसे स्विस बैंक के एकाउंट सहित राष्ट्रपति को पहुंचा दिया गया है।

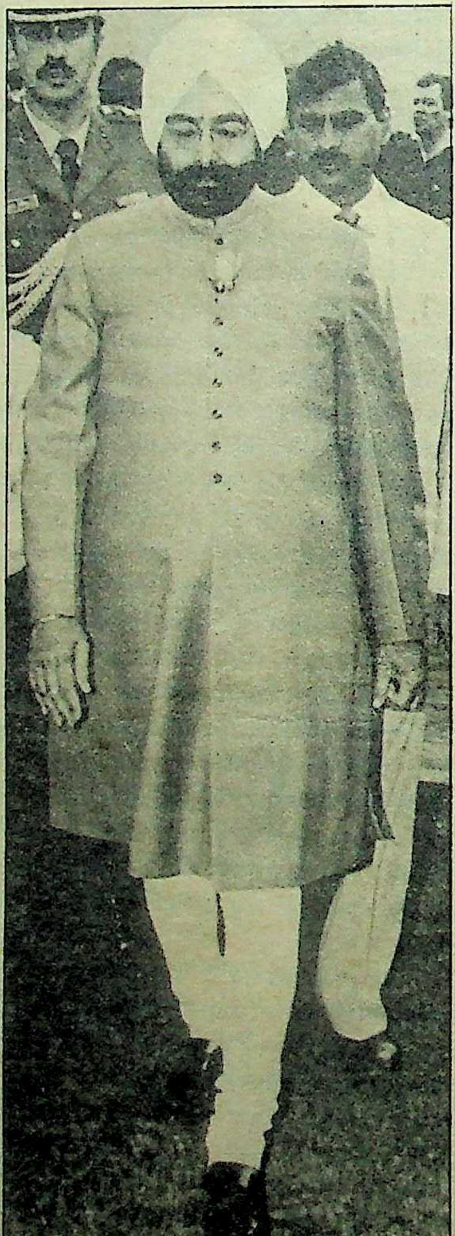
दोहरी चाल : ज्ञानी जैल सिंह

प्रेस में छपी अनेक कथाओं और अटकलबाजियों से दबाव का माहौल पैदा किया गया। अनेक बहुसंख्य कांग्रेसियों की रातों की नींद हराम थी और वे सार्वजनिक प्रदर्शन तक की उम्मीद कर रहे थे। किसी ने भी इन शंकाओं का खंडन नहीं किया। कल्पनाथ राय और उनके साथी वीपी सिंह की गद्दारी का प्रलाप करके लोगों का ध्यान बंटाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे।

जैल सिह उस पत्र कांड के बाद बड़ी चतुराई से खामोश हो गये और शासक तथा विपक्ष दोनों दलों में संशय व दुविधा की धुंध बढने दी। इस बीच यह भी अटकल लगायी गयी कि नये प्रधानमंत्री जैल सिह के साथ ही चन्द्रा स्वामी के अहसानमंद हो बोफोर्स का सौदा रद्द कर देंगे और दूसरा सौदा करेंगे, जिसमें अदनान खाशोगी को दलाली से अच्छी कमाई होगी।

इस पूरी योजना का तानाबाना दुबारा तब बुनना पड़ा, जब नरसिम्हाराव ने विनयपूर्वक उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल इसको इस तरह कहा गया कि उनका जैल सिह के राजीव को लिखे पत्र से कुछ लेना-देना नहीं है। दूसरी योजना के तहत कांग्रेस के १०० सांसदों का एक पत्र जैल सिह को भेजा जाना था, जिसमें यह बताया जाता कि राजीव गांधी व उनकी टोली पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से उनमें (राजीव में) उनका विश्वास नहीं रहा और उन्हें पार्टी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। अब ज्ञानी जैल सिह फरमा रहे हैं कि

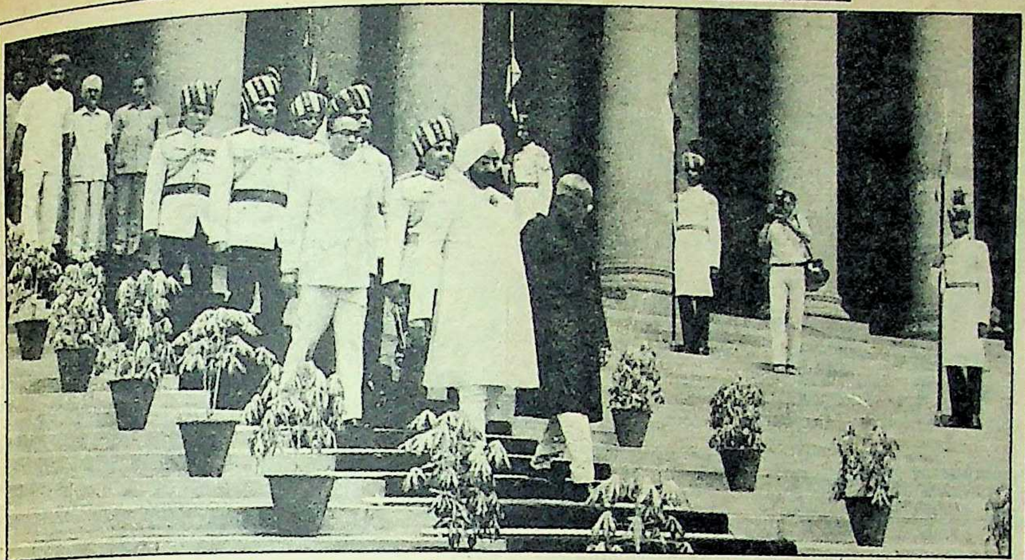

जरूरत के साथी : भूतपूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति

चौधरी बलराम जाखड़, अर्जुन सिह और हाल के मंत्रिमंडलीय फेरबदल में मंत्री बने एक युवा सांसद ने जो नाम पेश किये थे, उनकी संख्या २०४ थी। वैसे, उनके पास अनेक फेहरिस्तें हैं और इसके जरिये वह कुछ मंत्रियों को इस मामले में सान सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन फेहरिस्तों से ज्ञानीजी राजीव गांधी की भी मदद कर सकते हैं। चूं-चपड़ करनेवाले मंत्रियों के पर कतरने के लिए राजीव गांधी इन फेहरिस्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ज्ञानीजी को कोई नुकसान नहीं।

योजना का दूसरा चरण सफल नहीं हो सका, क्योंकि एक तो कोई भी पैरोकार पर्याप्त सांसद नहीं जुटा पाया और दूसरे वीपी सिह उस समय न विद्रोह करने के लिए रजामंद हुए और न राज़ीव की जगह लेने के लिए तैयार हुए।

वीपी सिंह को २४ जनवरी, १९८७ को वित्त से रक्षा विभाग में भेज दिये जाने के बाद भी जैल सिंह को विश्वास नही हुआ कि वीपी सिंह राजीव से क्षुब्ध होकर पाला बदल लेंगे। फरवरी में वीपी सिंह जब ज्ञानी जैल सिंह से ४५ मिनट तक मिले, तो अफवाह उड़ी थी कि वह राजीव गांधी को सत्ताच्युत करने के लिए जैल सिंह से साठगांठ कर रहे हैं। लेकिन यह अफवाह निराधार सिद्ध हुई, क्योंकि बाद में पता चला कि उन्होंने इस मुलाकात में राष्ट्रपति को समझाया था कि वह प्रधानमंत्री से अपने मतभेद दूर कर लें। बाद में १२ अप्रैल की सुबह भी वीपी सिंह ने एक समारोह में राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उसी दिन शाम को उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस दिन समारोह के बाद वीपी सिंह ने सपत्नीक राष्ट्रपति के साथ मुगल गार्डन में चाय पी थी। हालांकि, यह खास मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान भी राजीव गांधी को हटाने जैसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि जैल सिह दो महीने से अपने दोस्तों को इशारे से यह जता रहे थे कि जिस क्षण वीपी सिह तैयार हो जायेंगे, उसी दिन वह राजीव गांधी को बर्खास्त कर देंगे।

कारण कुछ भी रहा हो, वीपी सिंह इस अवसर पर चूक गये और जैल सिंह ने उन्हें कायर और गीदड़ संबोधित करना शुरू कर दिया। 'रविवार' साप्ताहिक को दी गयी भेंटवार्ता में तो इसे इन्होंने खुलकर कहा भी।

अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया, जबकि ज्ञानीजी ने विपक्षी समर्थन और महत्वाकांक्षी कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों पर भरोसा किया हो। बहरहाल, उन्होंने इन सबको यह भरोसा करने दिया कि ज्ञानीजी उनकी हर योजना के साथ हैं। एक, इस विश्वास में रहा कि उसे प्रधानमंत्री पर अभियोग चलाने की अनुमति मिल जायेगी, तो दूसरे को यह भरोसा हो गया कि ज्ञानीजी राजीव गांधी को बर्खास्त करनेवाले हैं, तो तीसरा यह समझे रहा कि ज्ञानीजी पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। विपक्षियों के पास प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न लोगों के नाम थे, जिनमें आर० वेंकटरमण का नाम भी शामिल था।

वास्तव में कुछ विद्रोही कांग्रेसी ऐसा मानते थे कि राजीव गांधी के खिलाफ संघर्ष में जैल सिंह के बजाय वेंकटरमण पर कहीं अधिक भरोसा किया जा सकता है। यही कारण है कि जैसे ही राजेश पायलट और दो अन्य मंत्रियों ने वेंकटरमण को सूचित किया कि कांग्रेस-इ पार्टी में उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाये जाने पर मतभेद हो गया है, तो तत्काल असंतुष्टों ने ज्ञानीजी को समर्थन देने का विचार त्याग दिया।

दूसरी ओर, ज्ञानीजी के अपने ही इरादे थे। वह वसंत दादा पाटिल, बलराम जाखड़ या वेंकटरमण में से किसी एक को राजीव गांधी के स्थान पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश दादा ने सामने आने में काफी देर कर दी। जाखड़ को न पंजाब से समर्थन मिला और न ही राजस्थान से तथा उन्हें आर्थिक मदद देनेवाले भी पीछे हट गये। वेंकटरमण को जैसे ही कांग्रेस-इ ने राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, वह इस योजना से बाहर हो गये। इस तरह राजीव गांधी पर अभियोग चलाने और उन्हें बर्खास्त करने के ज्ञानीजी के कथित मंसूबों पर पानी फिर गया, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह तक एक व्यक्ति आर्थिक मददगारों की जुगाड़ में लगा रहा। राजीव-विरोध को उकसाने में सक्रिय एक खास व्यक्ति ने कुछ पत्रकारों और नेताओं से मुलाकात करके बताया था कि राजीव गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए ज्ञानीजी को एक करोड़ रुपए और राजीव गांधी को बर्खास्त करने के लिए पांच करोड़ रुपए की पेशकश की गयी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यदि वास्तव में ज्ञानीजी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस हद तक गिरना स्वीकार कर लिया था, तो इससे अधिक धन तो वह ऐसा न करने के एवज में सत्तारूढ़ दल से प्राप्त कर सकते थे।

अब इस बात पर बहुत कम लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या अपने इस समूचे संकटपूर्ण काल में ज्ञानीजी सिर्फ इस उद्देश्य से राजीव गांधी को झुकाने पर आमादा थे, जिससे वह राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजीव सरकार से अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकें। ज्ञानीजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रमुख आर्थिक मददगार चंद्रा स्वामी कांग्रेस-इ नेताओं और रोमेश भंडारी से भी बराबर मिला करते हैं। पुराने कांग्रेसी होने के नाते वह यह भी जानते थे कि चुनावों के पहले कोई अपने नेता का साथ नहीं छोड़ता, न ही कोई सत्तारूढ़ व्यक्ति के साधन स्रोतों का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने देखा था कि श्रीमती गांधी ने अल्पमत में होते हुए भी सिर्फ इस वजह से मोरारजी देसाई और कामराज जैसे वरिष्ठ नेताओं को धूल चटा दी थी, क्योंकि वह तब प्रधानमंत्री थीं। वास्तव में एक कांग्रेस-इ सांसद (जिसने जून, १९८७ में राजीव का साथ छोड़ दिया था) ने राष्ट्रपति चुनावों के लिए नामांकन भरे जाने के कुछ सप्ताह पूर्व कहा था, "राष्ट्रपति चुनाव के बाद यदि ज्ञानीजी हमारा साथ छोड़कर फिर राजीव खेमे में चले जायें, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जबकि मैं वेंकटरमण पर हमेशा भरोसा कर सकता हूं।"

बहुत से लोग आश्चर्यचकित हैं कि कहीं अब जैल सिंह राजीव गांधी की कामराज जैसी योजना में लालबहादुर शास्त्री जैसी भूमिका तो नहीं निभा रहे अथवा क्या उन्होंने अब बदले की भावना त्याग दी है? ■

अफसर

कानून का पालन करें या आकाओं के हुक्म की तामील

नौकरशाही अपनी अजगरीवृत्ति और अड़ंगे लगाने की आदत के कारण बदनाम है। लेकिन क्या हमारे देश का राजनीतिक वातावरण ऐसा है कि अफसर स्वतंत्रता, कुशलता और न्यायसम्मत ढंग से काम कर सकते हैं? नेहरू-काल के बाद उच्चाधिकारियों के साथ सत्ताधारी नेता कैसा व्यवहार कर रहे हैं? राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद क्या नौकरशाही का मनोबल और ज्यादा गिरा है?

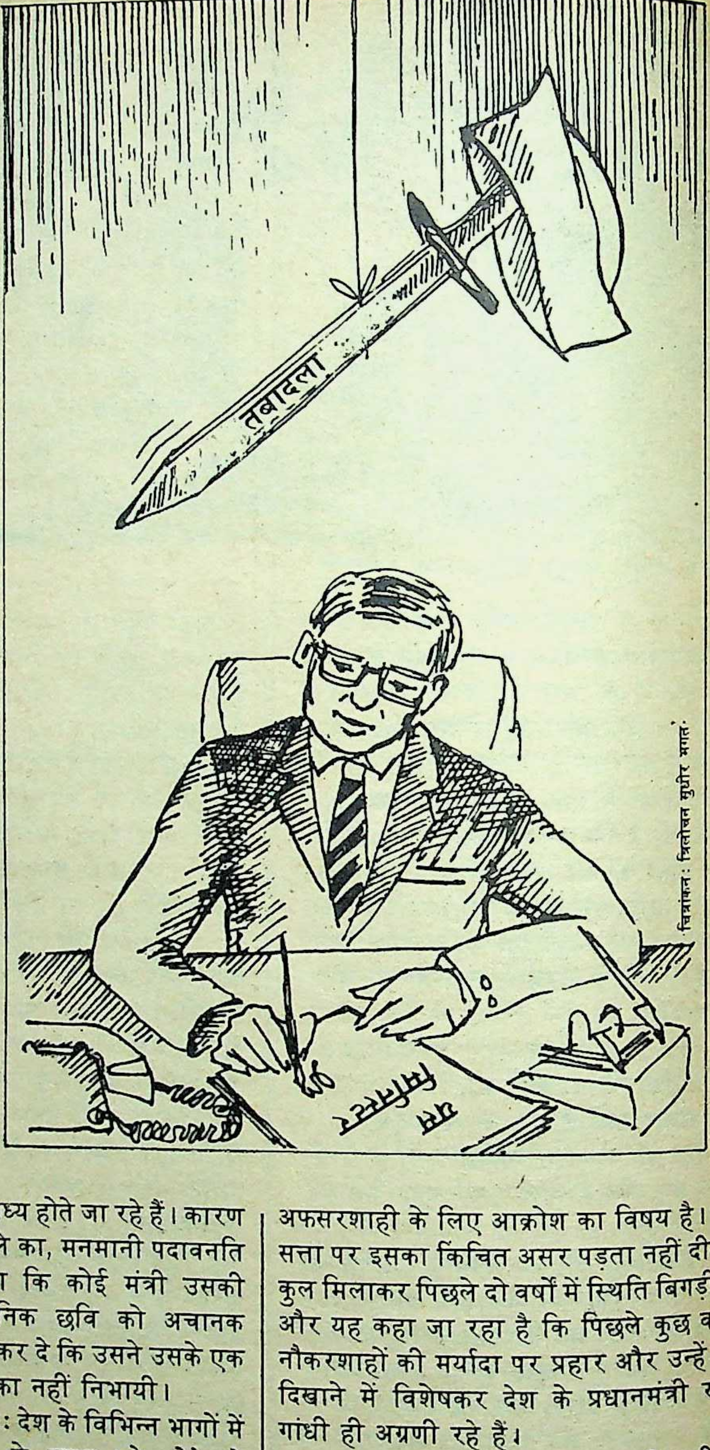

चित्रांकन : त्रिलोचन सुधीर भगत

पिछले दिनों जब केंद्र ने पंजाब की विधानसभा को भंग करने का एलान किया, तो इसका कारण यह दिया गया कि विधायकों के निरंतर हस्तक्षेप के कारण राज्य के अधिकारी आतंकवाद का मुकाबला पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहे थे। यानी, राजनीतिज्ञों की दखलअंदाजी से मुक्त होकर पंजाब का प्रशासन अब प्रभावशाली बन सकेगा और आतंकवादियों की खतरनाक, खूनी चुनौती का खुलकर मुकाबला कर सकेगा।

परंतु, क्या पंजाब के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में अफसर राजनेताओं के दुष्प्रभाव, हस्तक्षेप और उत्पीड़न से मुक्त हैं? क्या सत्ताधारियों और अधिकारियों के बीच का संबंध उसी पारस्परिक सद्भाव व सम्मान से अभी भी परिपूर्ण है जो ब्रिटिश काल व नेहरू युग की गौरवशाली परंपरा थी? क्या आज के अधिकांश अधिकारी, चाहे वे केंद्र में कार्यरत हों या राज्यों में, राजनीतिज्ञों के निरंतर मनमाने प्रहार से त्रस्त नहीं हैं? प्रायः यह देखने में आता है कि आज के अनेक अधिकारी अपनी स्वतंत्रता, निर्भीकता व निष्पक्ष प्रशासकीय कुशलता को तिलांजलि देकर सत्ताधारियों की 'जी हुजूरी' पर उतर आने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। कारण है भय—अचानक तबादले का, मनमानी पदावनति का और इस खतरे का कि कोई मंत्री उसकी (अफसर की) सार्वजनिक छवि को अचानक इसलिए धूल-धूसरित न कर दे कि उसने उसके एक 'निजी नौकर' की भूमिका नहीं निभायी।

मानसिक विक्षोभ: देश के विभिन्न भागों में इस मानसिक विक्षोभ से गुजर रहे छोटे-बड़े अनगिनत अधिकारी हैं। उनकी मनोभावनाएं क्या हैं, वे क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में? यह जानने के लिए 'माया' ने कुछ ऐसे ही अधिकारियों से बातचीत की। उनके अंदर छिपे क्लेश को कुछ ही शब्दों में भूतपूर्व विदेश सचिव, श्री ए०पी० वेंकटेश्वरन ने इस प्रकार रखा, "अब तो अफसरों को 'निजी नौकरों' की तरह इस्तेमाल करने का एक फैशन-सा हो गया है।" संभवतः वेंकटेश्वरन अभी तक उन क्षणों की वेदना से उबर नहीं पाये हैं, जब और कोई नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विदेश सचिव के पद से उनकी अचानक छुट्टी कर दी थी। अभी भी वेंकटेश्वरन का अभद्र [illegible] में संवेदनशील अफसरशाही के लिए आक्रोश का विषय है। परंतु, सत्ता पर इसका किंचित असर पड़ता नहीं दीखता। कुल मिलाकर पिछले दो वर्षों में स्थिति बिगड़ी ही है और यह कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाहों की मर्यादा पर प्रहार और उन्हें नीचा दिखाने में विशेषकर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही अग्रणी रहे हैं।

एन०आर० रेड्डी का मामला भी अभी लोग भूले नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री ने अपने विशेष सुरक्षा कार्य के लिए स्वयं चुना था। परंतु १९८६ में अंडमान द्वीप में छुट्टियों की मौज-मस्ती के दौरान उन्होंने रेड्डी से केवल अपनी कृपा दृष्टि ही नहीं हटा ली, बल्कि यह मौखिक आदेश भी दे दिया कि उन्हें उनके मूल छोटे पद पर तुरंत वापस भेज दिया जाये। यही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव वैद्यनाथन के साथ १९८५ में किया गया, क्योंकि उनसे कुछ मिनटों की ही बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने यह धारणा बना ली थी कि वह अयोग्य हैं। इस वर्ष, कुछ इसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार हुए कृषि व ग्रामीण विकास सचिव सुब्रह्मण्यम, जिन्हें पहले तो छुट्टी पर जाने का आदेश

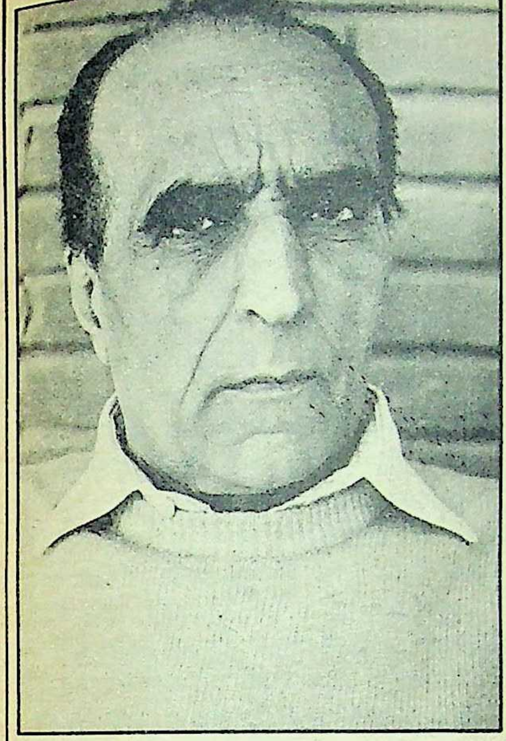

एस०एस० गिल

अचानक किया गया स्थानांतरण—कहीं दूर या किसी महत्वहीन पद पर—एक अधिकारी को घनघोर मानसिक यातना में ढकेल देने के लिए काफी होता है। खासकर, जबकि तबादला बार-बार हो। पारिवारिक जीवन को तो गहरा झटका लगता ही है, बच्चों की शिक्षा भी तबाह होती है।

दिया गया और बाद में अपने राज्य में उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया। कुछ दिनों पूर्व बंबई उच्च न्यायालय के एक निर्णय के फलस्वरूप यह बात भी खुलकर सामने आयी है कि किस तरह 'मनमानी और गैरकानूनी' ढंग से भूतपूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री टाइटलर ने एयर इंडिया के उपं-निदेशक हरीश कपूर को पहले अवकाश पर जाने के लिए बाध्य किया व बाद में एक वर्ष तक उन्हें निलंबित रखा। इस निर्णय के फलस्वरूप हरीश कपूर अपने पद पर पुनः आसीन हो सके हैं ज़बकि उनके सेवामुक्त होने में अब केवल चार सप्ताह ही वाकी रह गये हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में अधिकारीतंत्र का मनोबल एक गंभीर फिसलाव और गिरावट की दौर से गुजर रहा है।

प्रांतीय अफसर भी दुखी: राज्यों में भी संबंधित क्षेत्रों के मंत्री व विधायकों की इच्छानुसार जिलाधीशों व पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण किया जाना एक आम बात हो गयी है। राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक भी अकसर इसलिए नये सत्ताधारियों की निगाहों से दूर कर दिये जाते हैं, क्योंकि उनकी जगह ऐसे अधिकारियों को लाने की परंपरा बन गयी है जो वर्तमान मुख्यमंत्री का खुलकर जायज या नाजायज साथ दें। बदले में ऐसे अधिकारियों को मिलता है—सत्ताधारियों का खुला प्रश्रय व संरक्षण, जिसका नाजायज फायदा उठाना वह अपना हक समझ बैठते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के पुलिस महानिदेशक एस०एन० राय के साथ हुआ, जिनके विरुद्ध अनेक आरोप थे, परंतु वह अपने पद पर टिके रहे और निरंकुशता के शिखर पर जा पहुंचे, क्योंकि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के खास 'चहेते' थे, मूलतः वह मुख्यमंत्री की इच्छाओं की पूर्ति सदा बड़ी मुस्तैदी से किया करते थे। चूंकि एस०एन० राय को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त था, उनमें तानाशाही प्रवृत्तियां जरूरत से ज्यादा ही प्रभावी बन गयीं और उनके कार्यकाल में बिहार के गिने-चुने १४ ईमानदार पुलिस अधिकारियों को काफी दुर्गति का सामना करना पड़ा। अंततः जब भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बनाये गये, तो एस०एन० राय को पुलिस महानिदेशक के पद से मुक्त कर दिया गया। लेकिन क्या यह नहीं कहा जा सकता कि आगे भी नये मुख्यमंत्री का कोई विश्वासपात्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही इस पद पर आसीन रह सकेगा?

यदि राज्यों में यह एक परंपरा बन चुकी है तो उसका प्रेरणा स्रोत केंद्र ही रहा है। १९७७ में जब-जनता सरकार बनी, तो केंद्र में सभी अफसर स्थानांतरित कर दियें गये। जनता शासित राज्यों ने भी ऐसा ही किया। यही श्रीमती गांधी ने १९८० में पुनः सत्ता में आने के बाद किया। फिर, १९८२-८३ में राजीव गांधी के सहयोगियों द्वारा तैयार की गयी एक सूची के आधार पर ९० अधिकारियों का चटपट तबादला कर दिया गया और उनकी जगह कम आयु के लोग पदासीन किये गये। विश्वास था कि स्थानांतरित अफसरों की तुलना में, जिनके रिटायर होने में ५-६ वर्ष रह गये थे और जो किसी परिवर्तन के प्रति उत्साही नहीं रह गये थे, नये युवा अधिकारी प्रगतिशील नीतियों का न केवल अनुमोदन करेंगे, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिए काफी जोश व खरोश के साथ दिन और रात एक कर देंगे। परंतु, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी योजना धरी-की-धरी इसलिए रह गयी कि ये नये अधिकारी भी राजनीतिक दबाव के भंवर में फंसकर या तो बेबस हो गये या 'जी हुजूरी' का रास्ता अपनाकर अपनी ही तरक्की का आसान रास्ता अपना लिया।

कुव्यवस्था: इन प्रवृत्तियों का नतीजा यह हो रहा है कि देश शनैः-शनैः स्वतंत्र, निष्पक्ष व न्यायसंगत प्रशासन से वंचित होता जा रहा है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव दिन-प्रति-दिन के जनजीवन पर पड़ रहा है। प्रशासकीय क्षमता घट रही है, कुव्यवस्था आम बात होती जा रही है और कुल मिलाकर प्रजातंत्र की नींव खोखली होने लगी है। आज से ४० वर्ष पूर्व सरकारी मशीनरी को सुसंगठित करने के उद्देश्य से बनायी गयी गोपालास्वामी आयंगर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि "ऐसा सचिव देश के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध होता है जो अपने मंत्री द्वारा कही गयी सभी बातों में हां-में-हां मिलाता है। एक आदर्श सचिव वह है जो किसी मामले के दोनों पहलुओं को अपने मंत्री के सामने पूरी ईमानदारी व निष्पक्षता से रखे और यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दे कि मामले में क्या निर्णय सही होगा।" लेकिन समिति की यह बात जिस कागज पर लिखी गयी थी, वहीं रह गयी और विशेषकर वर्तमान विषम परिस्थितियों में, जहां निजी राजनीतिक व प्रशासनिक स्वार्थ देश पर हावी है, यह आशा रखना कि समिति की सलाह पर कोई चलेगा, हास्यास्पद है।

संघर्ष की पृष्ठभूमि: आजादी के प्रारंभिक वर्षों में अफसरशाही और मंत्रियों के बीच जो एक स्वस्थ व सकारात्मक सामंजस्य था, उसकी कल्पना आज बेकार है। उस समय संभवतः ऐसा इसलिए था कि स्वतंत्रता के संघर्षमय अनुभव व अनुभूतियों ने न केवल उन दोनों को परिपक्व बनाया था, बल्कि देश के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है, उसके प्रति भी वे काफी जागरूक थे। अपने मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन करने में उस समय अधिकारी न तो हीनता

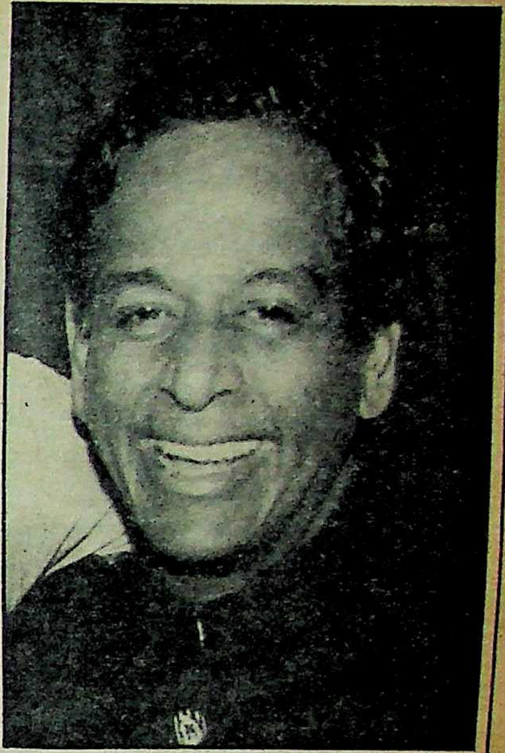

ए०पी० वेंकटेश्वरन

"अब तो अफसरों को 'निजी नौकरों' की तरह इस्तेमाल करने का एक फैशन-सा हो गया है।" संभवतः वेंकटेश्वरन अभी तक उन क्षणों की वेदना से उबर नहीं पाये हैं, जब और कोई नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विदेश सचिव के पद से उनकी अचानक छुट्टी कर दी थी।

महसूस करते थे और न किसी प्रकार भय, क्योंकि उन्हें उस समय यथेष्ठ सम्मान प्राप्त था, उनके विचारों की कद्र की जाती थी।

भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एक घटना का जिक्र करते हैं। १९४८ में उन्होंने पंडित नेहरू से पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति पंजाब के एक सरकारी अफसर के अनुचित व्यवहार की शिकायत की। नेहरू ने तुरंत ज्ञानीजी से कहा कि वह गृहमंत्री सरदार पटेल से बात करें, क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। जैल सिंह की शिकायत सुनने के बाद पटेल ने उन्हें आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, परंतु साथ में यह भी कहा, "आपको इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों को कुछ नियमों के अधीन कार्य करना पड़ता है और इन नियमों का ज्ञान उन्हें हमसे कहीं अधिक है। अतः हमें उनके प्रति उतावला रवैया नहीं अपनाना चाहिए।" परंतु नेहरू युग के बाद अफसरों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण आगे आने वाले वर्षों तक नहीं टिक सका। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ आई०सी० एस० धर्मवीर का कहना है, "जैसे-जैसे समय बीतता गया, राजनेता व मंत्री अपनी महत्ता के अहं में जरूरत से ज्यादा फूलते गये और वे अधिकारियों को अपना सलाहकार बनाने के बजाय उन्हें अपना नौकर मानने लगे। वे उन्हें हुक्म देने लगे, इस उम्मीद के साथ कि उनके हर हुक्म की तामील होनी ही चाहिए।" श्री धर्मवीर का यह भी कहना है कि मंत्रियों में ऐसी अवांछनीय प्रवृत्ति जगाने में कुछ अफसरों का भी हाथ रहा है जो कर्तव्यपालन के बजाय मंत्रियों की मदद के माध्यम से अपने निजी स्वार्थों की सेवा में मशगूल हो गये। प्रशासकीय सुधार समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी ओर संकेत किया था। यह सर्वविदित है कि आपातकाल में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी का अनुचित प्रश्रय पाकर किस प्रकार उनके विशेष सहयोगी, आई०ए०एस० अफसर एन०के० सिंह असामान्य रूप से प्रभावशाली हो गये थे।

राजीव का रवैया : कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर यह कहना है कि अफसरशाही की छवि को विशेषकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के गैर-जिम्मेदाराना कृत्यों से काफी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री बनने के ६ सप्ताह के अंदर ही उन्होंने २८ केंद्रीय सचिवों को स्थानांतरित किया और ४० सचिवों में से आधे को नये पदों पर फेंक दिया। सार्वजनिक रूप से किसी अधिकारी को न डांटने की एक स्वस्थ परंपरा जो पंडित नेहरू ने डाली थी, उसकी भी राजीव गांधी खुलकर अवमानना करते रहे हैं। भारत के भूतपूर्व गृह सचिव एल०पी० सिंह का कहना है कि १९५६ और १९७० के बीच भारत के तीन प्रधानमंत्रियों—नेहरू, शास्त्री व इंदिरा गांधी— ने शक अधिकारियों से साफ-सुथरी व योग्य सेवा की अपेक्षा रखी, परंतु उन्हें एक भी ऐसा मौका याद नहीं आता कि उस दौरान किसी भी प्रधानमंत्री ने अफसरों के प्रति अनुचित या असम्मानजनक व्यवहार किया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११ के अंतर्गत किसी प्रकार के अनुशासनात्मक दंड के विरुद्ध एक सरकारी अधिकारी को कुछ सुरक्षाएं अवश्य प्राप्त हैं। फिर भी एक मंत्री अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को परेशान कर सकता है जो उनके मनमुताबिक कार्य नहीं करते, बल्कि औचित्य व नियमों के आधार पर निर्णय लेने की 'जिद' करते हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए एक आम सजा है आजकल—तबादला। बर्खास्तगी या पदावनति के विरुद्ध तो संविधान का अनुच्छेद ३११ सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु तबादले के विरुद्ध नहीं। इसी का फायदा उठाते हैं मंत्री। भूतपूर्व सूचना व प्रसारण सचिव एस०एस० गिल के अनुसार, "अचानक किया गया स्थानांतरण—कहीं दूर या किसी महत्वहीन पद पर—एक अधिकारी को घनघोर मानसिक यातना में ढकेल देने के लिए काफी होता है। खासकर, जबकि तबादला बार-बार हो। पारिवारिक जीवन को तो गहरा झटका लगता ही है, बच्चों की शिक्षा भी तबाह होती है। किसी व्यक्ति को नष्ट करने का यह एक भयावह हथियार है।" और इसके दुरुपयोग पर कोई अंकुश नहीं। ऐसे ही तबादले की एक मिसाल का जिक्र होता है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक आई०पी०एस० अफसर को राजनीतिक अपराधों की जांच-पडताल का काम सौंपा गया था। कहा जाता है कि उसे श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा कथित आत्महत्या के प्रयास संबंधी आरोप की जांच के लिए कहा गया। अपनी निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के आधार पर उसने यह रिपोर्ट दी कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के विरुद्ध आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद वह अफसर केंद्रीय जांच ब्यूरों में नहीं देखा गया, उसका तबादला शायद कहीं दूर कर दिया गया था।

के०एफ० रुस्तमजी

श्री मारवाह दिल्ली के श्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक रहे हैं और उनके प्रति जो व्यवहार हुआ, उससे न केवल किसी योग्य अधिकारी की छवि को ही चोट नहीं पहुंचती है, बल्कि पुलिस के नैतिक बल में भी गिरावट आती है।

ऐसी विषम स्थिति को देखते हुए उनके अधिकारी व्यावहारिक नीति अपनाने के लिए विवश हो गये हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने भी अपना 'राजनीतिकरण' स्वीकार लिया है और अपने 'राजनीतिक मालिकों' का आदेश अक्षरशः पालन करने लग गये हैं। निःसंदेह, प्रशासन के स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि कोई अधिकारी किसी विशेष मंत्री का आदमी माना जाता है, तो उसका भविष्य भी उसी मंत्री के भविष्य के साथ जुड़ा होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटने के बाद विनोद पांडे और भूरे लाल पर क्या बीती, यह सभी को मालूम है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह किस प्रकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कोप के शिकार हुए, यह भी सर्वविदित है। के०एफं० रुस्तमजी का कहना है कि श्री मारवाह दिल्ली के श्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक रहे हैं और उनके प्रति जो व्यवहार हुआ, उससे न केवल किसी योग्य अधिकारी की छवि को ही चोट नहीं पहुंचती है, बल्कि पुलिस के नैतिक बल में भी गिरावट आती है।

जिन विषमताओं में आज का अधिकारी घिरा है, क्या उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ? जिन अधिकारियों से 'माया' ने बातचीत की, उनमें से अधिकतर निराश और मायूस ही लगे। वे महसूस करते हैं कि जब तक राजनीतिक शक्ति उनकी सहायता नहीं करती, तब तक उनकी स्थिति संभवतः और अधिक बिगड़ती जायेगी। वेंकटेश्वरन कहते हैं कि तबादलों को नियमित किया जाना चाहिए, कानून के द्वारा तबादले की शक्ति के राजनीतिक दुरुपयोग पर बंदिश लगानी चाहिए। परंतु राष्ट्रपति सचिवालय के एक वर्तमान सदस्य डा० पी०आर० दुबाशी का कहना है कि आमतौर पर अधिकारियों का स्थानांतरण जनहित में किया जाता है। उनका खयाल है कि तबादले के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाता। लेकिन डा० दुबाशी के इस मत से कुछ ही लोग सहमत हैं। अधिकतर अधिकारी नाउम्मीदी ही व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि उन पर राजनीतिक दबाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और सत्ता में जो भी दल है, केवल उसके हितों की रक्षा करना ही उनकी मजबूरी होती जा रही है—चाहे ऐसा करना नियमों के अनुरूप हो या विपरीत, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए इस महान देश के प्रबंध में नौकरशाही की भूमिका सिमट कर अब इतनी ही रह गयी है। परिवर्तन की आशा नहीं है। रोशनी यदि कहीं है भी, तो शायद काफी दूर है, दीखती नहीं।

—पद्मा शास्त्री व ममता मसीन

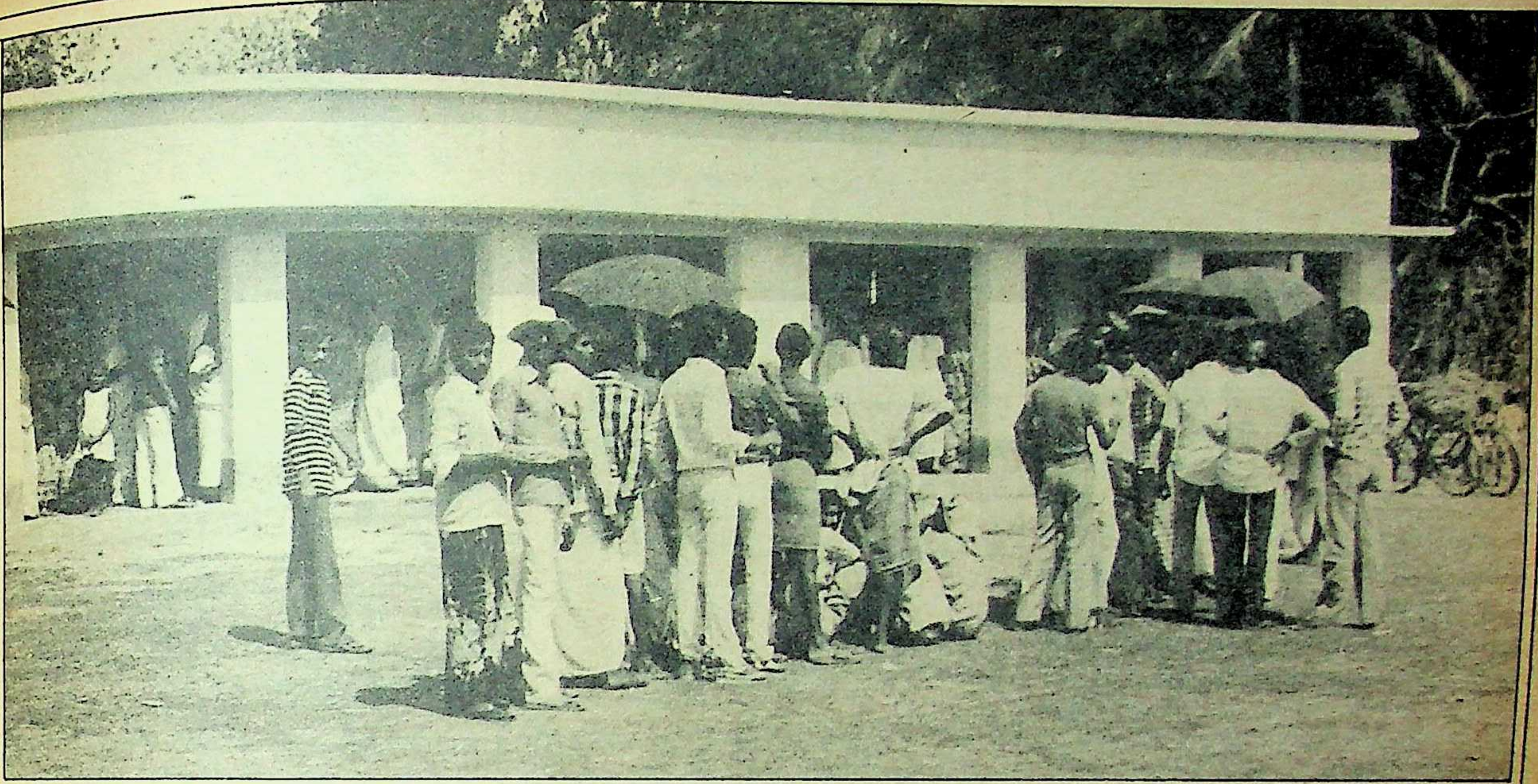

मार्क्सवादियों पर धांधली का आरोप: पंचायत चुनावों में एक मतदान केंद्र पर मतदान का दृश्य

पंचायत चुनाव

वाम मोर्चे में दरार

पश्चिम बंगाल में हुए ग्राम पंचायतों के चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्ववाले वाम मोर्चे ने कांग्रेस-इ को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस-इ पिछले पंचायत चुनावों में जहां ३२.२५ प्रतिशत सीटें हासिल कर सकी थी, वहीं इस बार वह २२ प्रतिशत से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, उसे दस हजार सीटों पर वाम मोर्चे का मुकाबला करने के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। इसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पंचायत चुनावों की भारी विजय के साथ ही वाम मोर्चे के टूटने की शुरुआत भी हो गयी है। स्वयं वाम मोर्चे के मंत्री व नेता ही अपनी सरकार पर पंचायत चुनावों में धांधली करने के आरोप क्यों लगा रहे हैं?:

संवैधानिक संकट ?: ज्योति बसु

पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की भारी विजय के बावजूद वहां आलम यह है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध मंत्रियों ने, सीपीएम के विरुद्ध मोर्चे के घटक फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी ने तथा राज्य सचिव के विरुद्ध उप सचिवों ने अविश्वास व्यक्त करते हुए, आरोपों की बौछार शुरू कर दी है।

१ मार्च को ही कोचबिहार के फारवर्ड ब्लाक कार्यालय में पश्चिम बंगाल के कृषिमंत्री कमल गुहा ने २८ फरवरी को हुए पंचायत चुनाव को लेकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध आतंक फैलाने और रिगिंग करने की दूसरी बार शिकायत की। इसके पहले वाम मोर्चा सरकार के सिचाई मंत्री देवव्रत वंद्योपाध्याय, सहकारिता मंत्री भक्तिभूषण मंडल, कारागार मंत्री विश्वनाथ चौधरी और पुस्तकालय मंत्री सरल देव भी सार्वजनिक रूप से ऐसा वक्तव्य दे चुके थे।

इन सभी मंत्रियों ने अपने-अपने जिले में सीपीएम द्वारा आतंक फैलाये जाने की बात कही है। इन्हीं लोगों के स्वर-से-स्वर मिलाकर फारवर्ड ब्लाक की प्रदेश इकाई के सचिव अशोक घोष ने भी सार्वजनिक रूप से ज्योति बसु को असत्यभाषी कहा और चुनावों के पूर्व ही आशंका व्यक्त की थी कि इस बार पंचायत चुनाव में कोई मतदाता निर्भय होकर मतदान नहीं कर सकेगा।

पंचायत चुनाव के दिन तक ज्योति बसु ने इन आरोपों को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि वैसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल में दरार पड़ती। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जो प्रेस कांफ्रेंस हुई, उसमें यह दरार साफ उजागर हो गयी। उसमें ज्योति बाबू ने स्वीकार किया कि मंत्रियों की बातों से सरकार के प्रति विरोध की भावना प्रकट हुई है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री ज्योति बसु अब जनता

का उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में त्रिपुरा में हुए आम चुनाव का जो परिणाम सामने आया, उससे ज्योति बाबू विचलित हैं।

ज्योति बसु और सीपीएम सचमुच इस समय भयानक राजनीतिक संकट में हैं। केरल में भी सीपीएम नेतृत्व की जड़ में सड़न शुरू हो गयी है। इसका प्रमाण उस राज्य में हुए पंचायत चुनावों के परिणाम हैं। सीपीएम नेतृत्ववाले मंत्रिमंडल के तत्वावधान में संपन्न चुनाव में सीपीएम की हार हुई। लेकिन सीपीएम को बड़ा धक्का त्रिपुरा में लगा। दस वर्षों से उस राज्य में सत्ता सीपीएम के पास रही जो इस बार आम चुनाव के बाद हाथ से निकल गयी। इस घटना से एक तरफ सीपीएम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मुरझाये हुए कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है। इस बार पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सफाया कर सीपीएम ने उस धक्के को संभालना चाहा था, लेकिन व्यवस्थित चुनाव के जरिये उसके लिए वैसा करना संभव नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि संभवतः उन्हें पहले आतंक का तथा बाद में मतदान में धांधली का सहारा लेना पड़ा।

विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस-इ का आरोप है कि सीपीएम ने आतंक फैलाकर दस हजार सीटों के लिए अन्य दलों को प्रत्याशी ही खड़ा करने नहीं दिया और इन सीटों पर सीपीएम प्रत्याशी निर्विरोध जीते। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जहां विधान सभा और लोकसभा के खर्चीले चुनाव में खड़े होने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लग जाती है, वहां गांव-देहात के इस पंचायत चुनाव में सीपीएम के भय से विपक्षी दलों को दस हजार सीटों के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले। इतने दिनों तक जो शिकायत कांग्रेस-इ करती रही, अब वही शिकायत ज्योति बाबू के मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी खुलकर करने लगे।

दरार की शुरुआत : दरअसल, चुनावों के पूर्व चुनावी तालमेल के सवाल पर ही वाम मोर्चे में दरार पड़ गयी थी। करीब १५ हजार सीटों पर सीपीएम से वाम मोर्चे के घटक आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के बीच कोई समझौता नहीं हो सका और इन सीटों पर वाम मोर्चे के घटक एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़े। सिदड़ी की चुनाव सभा में ज्योति बाबू ने जो कुछ कहा, उससे यह दरार और भी चौड़ी हो गयी। उन्होंने कहा था, "आरएसपी या फारवर्ड ब्लाक को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। इन दलों ने मोर्चे की नीति का पालन नहीं किया है। इसलिए जिन सीटों पर सीपीएम के विरुद्ध आरएसपी या फारवर्ड ब्लाक के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सीपीएम प्रत्याशियों को ही वोट दीजिए। केवल सीपीएम ने ही मोर्चे की नीति के अनुसार प्रत्याशी खड़े किये हैं।" ज्योति बाबू ने यह भी कहा था कि फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी ने बहुत अधिक सीटों की मांग की थी, इसलिए चुनावी तालमेल नहीं हो सका तथा इस बिखराव के लिए ये दल ही जिम्मेदार हैं, अतः आप लोग इन्हें वोट न दें।

> पश्चिम बंगाल में जहां विधानसभा और लोकसभा के खर्चीले चुनाव में खड़े होने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लग जाती है, वहां गांव-देहात के इस पंचायत चुनाव में सीपीएम के भय से विपक्षी दलों को दस हजार सीटों के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले। इतने दिनों तक जो शिकायत कांग्रेस-इ करती रही, अब वही शिकायत ज्योति बाबू के मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी खुलकर करने लगे।

इस वक्तव्य के बाद तो आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के नेताओं ने ज्योति बाबू के खिलाफ आग उगलनी प्रारंभ कर दी। बीरभूम की विभिन्न जनसभाओं में सहकारिता मंत्री भक्तिभूषण ने गर्जना की, "मंत्री-पद खोने से नहीं डरता, इसलिए ज्योति बाबू और सरोज मुखर्जी आदि को सावधान कर देता हूं कि वे आंखें लाल-पीली करके फारवर्ड ब्लाक को ठंडा नहीं कर सकते।"

उसके बाद आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के अन्य नेताओं और इन पार्टियों से जुड़े मंत्रियों ने खुलकर सीपीएम के रवैये का विरोध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक तरफ सीपीएम नेताओं और मंत्रियों तो दूसरी तरफ वाम मोर्चे में शरीक फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी नेताओं और मंत्रियों के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुए, उसने पंचायत चुनावों में हुई वाम मोर्चे की जीत का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया।

पंचायत चुनाव कैसे हुए ? : ऐसे माहौल में २८ फरवरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। इस दौरान अनेक स्थानों पर गोली चली, एक सौ से अधिक लोग घायल हुए और दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के अनुसार, इस चुनाव में मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतपत्र छीनना और मतगणना में अनियमितता आदि सब कुछ हुआ। लेकिन सीपीएम और मुख्यमंत्री ज्योति बसु के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी दबाव के हुआ। पश्चिम बंगाल कांग्रेस-इ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस फर्जी चुनाव की जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखा है। श्री दासमुंशी का आरोप है, "चुनाव के पहले ज्योति बाबू ने शातिर अपराधियों को जेल से छोड़ा था, ताकि वे हंगामा खड़ा कर सकें और आतंक फैला सकें। कोचबिहार में बारह हजार और मेदिनीपुर में चौवन हजार ऐसे समाजविरोधी और अपराधी हैं जो इस समय सीपीएम के कार्यकर्ता हैं और उनके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे विचाराधीन हैं। इन लोगों ने एक तरफ आतंक फैलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर से और मतदान केंद्र से भगाया, तो दूसरी तरफ मतगणना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। फर्जी मतपत्र डालकर सीपीएम के पक्ष में बहुमत दिखाया गया। इसके पहले मतदाता सूचियों में जालसाजी की भरभार की गयी। उनमें दस-बारह वर्ष के नाबालिग लड़कों के अतिरिक्त उन लोगों को भी मतदाता बनाया गया, जिनकी मृत्यु दस वर्ष पहले हो चुकी थी। इन सभी मतदाताओं ने सीपीएम के पक्ष में मतदान किया।"

फर्जी चुनाव : प्रियरंजन दास मुंशी

धांधली के सबूत : विभिन्न जिलों से आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के नेताओं ने भी ऐसी ही शिकायतें कीं। आरोप है कि मालदा में फारवर्ड ब्लाक के अध्यक्ष विधायक बीरेन मैत्र के सीने से बंदूक की नली लगाकर सीपीएम समर्थकों ने उनको अंतिम चुनाव सभा में जाने से रोका। फारवर्ड ब्लाक की ही एक अन्य विधायक अपराजिता गोप्पी पर उस समय घातक हमला हुआ, जब वह किसी जनसभा को संबोधित करने जा रही थीं। फारवर्ड ब्लाक की प्रदेश कमेटी ने ये दोनों शिकायतें की हैं। यह भी शिकायत है कि सीपीएम के आतंक के कारण आरएसपी सांसद सनत मंडल सामान्य ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर सके। चुनाव के बाद वह घर से दूर रहने लगे। आरोप है कि मतदान केंद्रों को घेरकर या उन पर कब्जा कर सीपीएम समर्थकों ने अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए चुनाव अधिकारियों को बाध्य किया। पश्चिम बंगाल के अधिकांश ग्रामीण केंद्रों पर बिजली नहीं है। वहां मिट्टी के तेल की टिमटिमाती रोशनी में मतगणना का लाभ उठाकर सीपीएम समर्थकों ने पुलिस कर्मचारियों और चुनाव अधिकारियों की मदद से जाली मतपत्रों को असली बनाकर अपना बहुमत

सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार रात के अंधेरे में असली मतपत्र रास्ते में और जलाशयों में फेंके गये। ऐसे ३५ मतपत्र कृष्ण नगर में बरामद हुए। इन मतपत्रों पर कांग्रेस-इ के चुनाव चिह्न 'पंजे' का ठप्पा लगा था। जब ये मतपत्र मिले, तब उस केंद्र में मतगणना समाप्त हो चुकी थी। ये मतपत्र नवद्वीप नंबर ४ मतदान केंद्र के थे। इन पर बाकायदा केंद्र की मुहर (एनडीपी-४) भी हैं और इस केंद्र के चुनाव अधिकारी राधाकृष्ण चक्रवर्ती के हस्ताक्षर भी। इन मतपत्रों की क्रम संख्या इस प्रकार है :—

१०२६२३ १०३१९१ १०२६०९
१०२६८४ १०२५१२ १०२६१४
१०३२६५ १०३०५५ १०२६३६
१०३००५ १०२६७६ १०३०३७
१०३२४४ १०२६१० १०२५६५
१०२६९८ १०२५२० १०३२०६
१०३०१० १०३२४७ १०३१५०
१०३१३० १०३०३५ १०२६१३
१०२५११ १०३०३६ १०२५१९
१०३२५६ १०२६९६ १०२६९७
१०३२४८ १०३१८३ १०२६४८
१०२६३५ १०२५१३

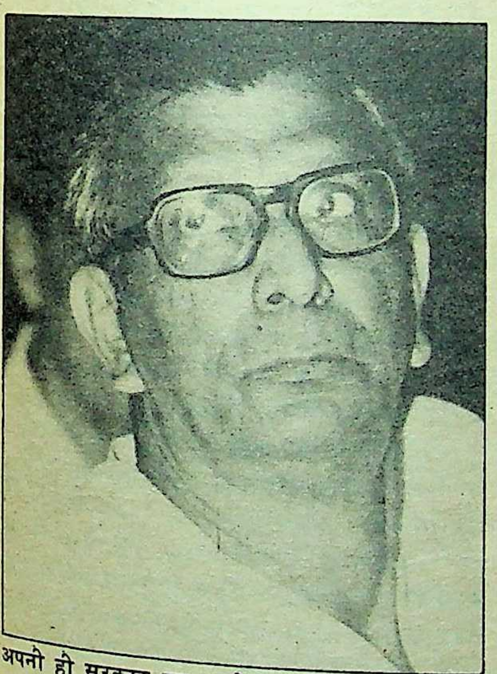
अपनी ही सरकार पर आरोप: सिंचाई मंत्री देवव्रत बनर्जी

यही स्थिति बारासत क्षेत्र में भी रही। चुनाव के बाद चौबीस परगना जिले में सीपीएम के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी घर से भागे हुए हैं। फारवर्ड ब्लाक के जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की गयी। पश्चिम बंगाल के पुस्तकालय मंत्री सरल देव के अनुसार इस दौरान पुलिस निष्क्रिय बनी रही। इस प्रकार विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार मार्च के दूसरे हफ्ते तक पूरे पश्चिम बंगाल में ९८ हजार, ७ सौ राजनीतिक कार्यकर्ता घर से भागे रहे। सीपीएम के डर से वे घर नहीं लौट सके। ऐसी स्थिति में प्रियरंजन दासमुंशी ने सूचना दी कि मौके पर इसकी जांच के लिए केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह आ रहे हैं। इसका ज्योति बसु ने तत्काल जवाब दिया, "अच्छा होगा बूटा सिंह दार्जिलिंग के लिए सीआरपी की बटालियन लेकर आयें।"

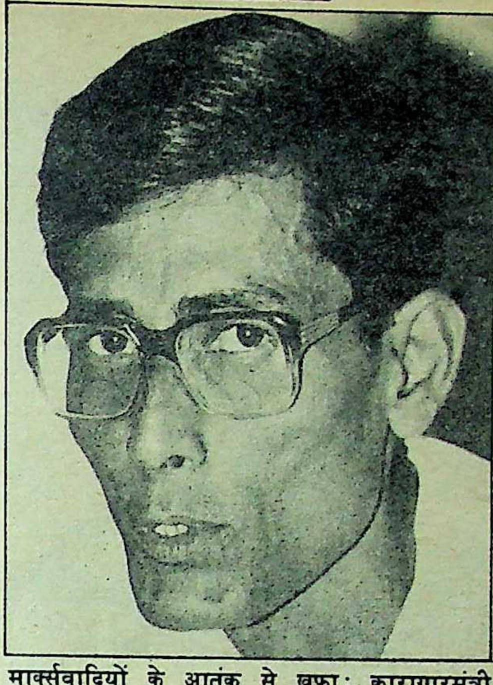
मार्क्सवादियों के आतंक से खफा: कारागारमंत्री विश्वनाथ चौधरी

संवैधानिक संकट: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर कांग्रेस-इ जहां पंचायत चुनावों में धांधली करने का आरोप लगा रही है, वहीं यह भी एक वास्तविकता है कि कांग्रेस-इ की चुनाव रणनीति भी उसकी हार के लिए जिम्मेदार रही है। प्रियरंजन दास मुंशी चुनाव सभाओं में यह धमकी भी देते थे कि यदि वाम मोर्चे की सरकार प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करने में कामयाब नहीं रही, तो केंद्र सरकार यहां आपातकाल लागू करने में भी नहीं हिचकिचायेगी। राज्य के लोगों को साठ के दशक के अंत में पश्चिम बंगाल में लगे आपातकाल का तीखा अनुभव था। इस कारण दासमुंशी का यह वक्तव्य मतदाताओं को रास नहीं आया। कहा तो यह भी जा रहा है कि दासमुंशी अपनी अक्षमता पर परदा डालने के लिए वाम मोर्चे पर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वाममोर्चा सरकार के मंत्रियों द्वारा अपनी सरकार की ही आलोचना करने पर दासमुंशी ने आरोप लगाया है कि प० बंगाल में 'संवैधानिक संकट' उपस्थित हो गया है, क्योंकि ज्योति बाबू अपने ही मंत्रियों का विश्वास खो चुके हैं। दूसरी ओर ज्योति बाबू उसे 'राजनीतिक संकट' की संज्ञा देते हैं।

बहरहाल, 'संवैधानिक संकट' के आरोप को झूठा साबित करने के लिए अब फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी के नेताओं से ज्योतिबाबू मतभेदों को भुला देने की अपील कर रहे हैं। उक्त दोनों दलों के वरिष्ठ नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, लेकिन वाम मोर्चे के कायेकताओं में पडी दरार कितनी चौड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाम पंथी दलों के १५ मार्च के भारत बंद के सिलसिले में पश्चिम बंगाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित जुलूसों और सभाओं में भाग लेने से फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी के कार्यकर्ताओं ने इनकार कर दिया।

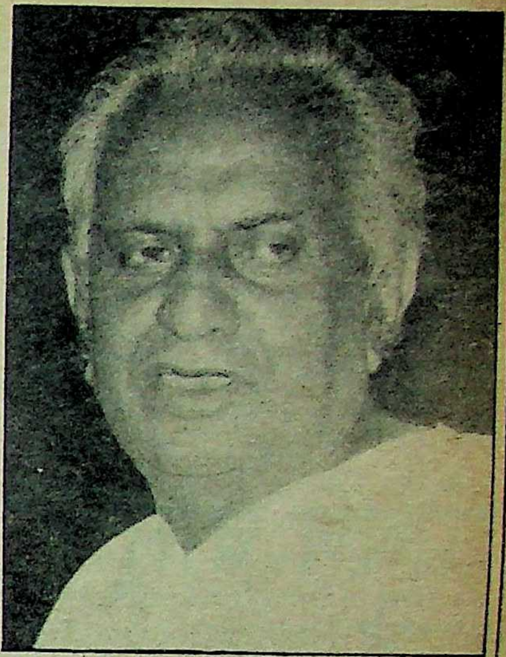
मंत्री-पद खोने से नहीं डरता: सहकारिता मंत्री भक्ति भूषण मंडल

पंचायत चुनावों का असर: इस प्रकार इस पंचायत चुनाव में सीपीएम के विरुद्ध लड़कर आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक के कार्यकर्ता जिस तरह पिटे, उससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले किसी चुनाव में वाम मोर्चे के बाहर रहनेवाले कम्युनिस्टों और वामपंथी दलों से मिलकर ये दोनों दल, अपना अलग मोर्चा बना सकते हैं। आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक का नक्सली गुटों, एसयूसी और एआईसीपी से अच्छा संबंध है। तीसरा मोर्चा बन जाने पर सीपीएम के लिए परेशनी होगी, क्योंकि विधान सभा के पिछले चुनाव में वाम मोर्चा ३२ प्रतिशत मत पाकर विजयी हुआ था। तीसरा मोर्चा बन जाने पर कांग्रेस के समर्पित मतों के मुकाबले सीपीएम की हार सुनिश्चित होगी।

क्या त्रिपुरा की तरह प० बंगाल से भी मार्क्सवादियों के पैर उखड़ने की भूमिका बनने लगी है? वैसे भी पश्चिम बंगाल में १९६७ व १९६९ में बनी मोर्चे की सरकारें सफल नहीं रही थीं। १९७९ में केंद्र में भी विभिन्न दलों के विलय से बनी जनता पार्टी की सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी थी। फिर भी राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि ज्योति बाबू अपनी सूझबूझ से मोर्चे में पड़ी फूट को दूर करने में कामयाब हो जायेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस-इ के लिए भी इस चुनाव का प्रभाव महत्वपूर्ण है। वाम मोर्चे के घटकों के आपसी कलह से और ग्रामीण क्षेत्रों में मार खाने से कांग्रेस-इ को सबक मिला है कि सिर्फ हवा बांधने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए अच्छी तैयारी और आतंक का जवाब देने की ताकत होनी चाहिए। इस कारण जिला और ब्लाक कमेटियों के पुनर्गठन की मांग होने लगी है। इस मांग के पीछे हैं, कांग्रेस-इ के प्रदेश सचिव सोमेन मित्र।

—रमाप्रसाद घोषाल, हबीब अहसान

आदिवासी

शोषण चालू आहे

इसी वर्ष महाशिवरात्रि पर १६ फरवरी, १९८८ को ठाणे की वाड़ा स्थित आदिवासी आश्रम शाला में शहर से आये नव धनाढ्य ऐयाश युवकों ने आदिवासी छात्राओं के साथ बलात्कार करने की नाकाम कोशिश की। यदि इन छात्राओं ने अपने कमरों की सांकलें अंदर से बंदकर साहसपूर्वक प्रतिरोध न किया होता, तो उन्हें वहां कोई बचा नहीं सकता था। नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस एक सांसद और एक प्रभावशाली विधायक के कारण कुछ नहीं कर सकी। इसी ताल्लुका के एक अन्य आदिवासी क्षेत्र का हाल तो यह है कि यहां की अधिकांश आदिवासी लड़कियां कुंवारी रह गयी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब यहां के एक भूमिपति की हवस का शिकार हो चुकी हैं, नतीजतन कोई उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होता। यह इलाका बंबई से सिर्फ ६०-७० किलोमीटर दूर है, जहां पुलिस और प्रशासन आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के उन ६३ लाख से अधिक आदिवासियों के शारीरिक और आर्थिक शोषण का मंजर क्या है, जहां पुलिस का आसानी से पहुंचना संभव नहीं है? महाराष्ट्र के इन आदिवासियों के हालात का जायजा:

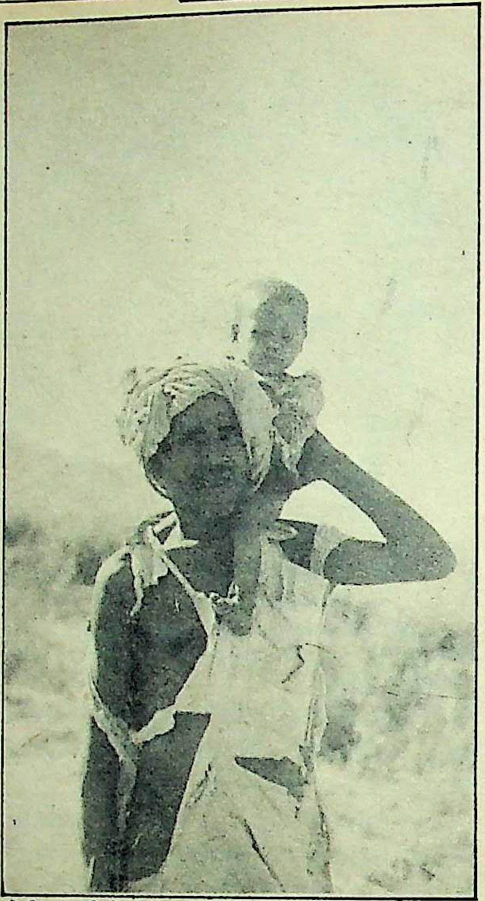

पीढ़ी-दर-पीढ़ी अभिशप्त जीवन: कंधे पर बच्चा लिए एक आदिवासी

फरवरी का दूसरा पखवाड़ा। अकोला स्थित संगमनेर ताल्लुका के निचले हिस्से में प्रवरा नदी के तट का आदिवासी इलाका। खेतों-जंगलों में क़ाम कर वापस लौटने के बाद आदिवासी स्त्री-पुरुष रात के भोजन-पानी के जुगाड़ में लगे थे कि उन्हें अचानक खबर मिली कि सरकारी गाड़ियों में सवार सरकारी आदमी प्रवरा नदी पर बनी लिफ्ट को तोड़ने आ रहे हैं। यह खबर आसपास के आदिवासी गांवों में आग की तरह फैली और बर्तन-चूल्हा वैसे ही छोड़ कर स्त्री-पुरुष और बच्चे, जिनके हाथों में जो कुछ भी आया, उसे लेकर लिफ्ट के निकट जा पहुंचे। आधे घंटे के भीतर क्रुद्ध हजारों आदिवासी वहां एकत्र हो गये और पूरी रात वहां पहरा देते रहे। इसके बाद से सरकारी मुलाजिमों के चंगुल से लिफ्ट को बचाने के लिए वे हर रात वहां एकत्र होकर पहरेदारी करने लगे। पहरेदारी का यह सिलसिला न केवल काफी दिनों तक चला, बल्कि एक घंटे के आह्वान पर ५० हजार से अधिक आदिवासियों ने एकत्र होकर लिफ्ट न तोड़ने के लिए प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों ने खुलकर उनका साथ दिया और उनकी वकालत की जिला इंका अध्यक्ष राजा बाबू भांगरे ने।

प्रवरा नदी के आदिवासियों के लिए गंगा के समान है। वहां लिफ्ट बांधकर वे रोजमर्रा के काम के लिए पानी उपलब्ध करते हैं। लिफ्ट तोड़ दिये जाने के बाद उनके सामने जीवन-मरण की समस्या उत्पन्न हो जाती। जल-संकट की यह समस्या सिर्फ अकोला के ही आदिवासियों की नहीं समूचे महाराष्ट्र के लाखों आदिवासियों की है। उन्हें यह जल नर्मदा, मूला, अडरा आदि छोठी नदियों से भी प्राप्त होता है। इन नदियों के निकट-स्थित चीनी कारखाने एवं दूसरी मिलें पानी का अधिकांश भाग ले जाती हैं, फलतः जगह-जगह पर आदिवासियों ने लिफ्ट बांधकर अपने लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है।

नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका ९० प्रतिशत बहाव पहाड़ी क्षेत्रों में है। इसीलिए उनके किनारे रहनेवाली ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है। पूरा क्षेत्र दुर्गम होने तथा संचार-साधन से कटे होने के कारण उनके बारे में कोई जानकारी शहरों तक नहीं पहुंच पाती। लगभग छह महीने पूर्व धुलै जिले के ४० से अधिक आदिवासियों की रहस्यमय मृत्यु की खबर क़ाफी विलंब से नगरों तक पहुंची। इस पर हंगामा होने पर पहली बार डाक्टरों का दल जांच के लिए पैदल इन आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचा और उन्हें मुफ्त दवाएं उपलब्ध करायीं। सरकारी सूत्रों के अनुसार उनकी मौत सिक्कल सेल तथा दूसरी बीमारियों के कारण हुई थी। सिक्कल सेल यानी खून में हंसिये के आकार की कोशिकाओं की मौजूदगी आदिवासियों में बीमारी का प्रमुख कारण है। दो वर्ष पूर्व इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार के एक अध्ययन दल ने जांच के बाद रिपोर्ट दी थी, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ।

दरअसल, उनकी सबसे बड़ी बीमारी तो समुचित पोषक आहार की कमी है। जंगलों में जड़ों तथा फलों पर जीवन-निर्वाह करते लोगों तक पोषक खाद्य नहीं पहुंच पाते। अनेक मृत्यु-कांड तो सरकारी कागजों में दर्ज ही नहीं होते।

बेदखली के शिकार: पूरे महाराष्ट्र के वन क्षेत्रों में केवल यही समस्या नहीं है। आदिवासी बेदखली के भी शिकार हो रहे हैं। १९७८ में तत्कालीन राजस्वमंत्री-राजाराम बापू पाटील ने निर्देश दिये थे कि जिस वन-भूमि पर आदिवासी वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें उसके पट्टे दे दिये जायें। इसे कानूनी जामा तो पहना दिया गया, परंतु आज तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ। राज्य में लाखों आदिवासी जिस जमीन पर बरसों से बसे हुए हैं, उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। धुलै जिले के शिरपुर तहसील में एक गांव है चिंचपानी। स्थानीय भाषा में चिंचपानी का मतलब है, इमली का रस। वही उनका जीवन सत्व है, वही मुख्य आहार, लेकिन जंगलों की बड़े

साक्षात्कार/डा० श्रीकांत जिचकार

वन कर्मचारियों के उत्पीड़न से आदिवासियों को बचाया जाये

महाराष्ट्र के सूचना तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री डा० श्रीकांत जिचकार हाल ही भामरागढ़ के दुर्गम जंगलों में रहनेवाले माड़िया आदिवासियों के हालात का जायजा लेकर लौटे हैं। वह बिना सरकारी तामझाम के वहां पहुंचे थे। प्रस्तुत हैं, 'माया' से हुई उनकी बेबाक बातचीत के अंश :

माया : महाराष्ट्र के दुर्गम भामरागढ़ का आपने दौरा किया था? इसका मकसद क्या था?

जिचकार : किसी भी कल्याणकारी राज्य में योजना बनाते समय वंस्तुस्थिति की जानकारी तथा उसके क्रियान्वयन में संभावित कठिनाइयों का पता रहना चाहिए। यही सोचकर मैंने मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण से अनुमति मांगी तथा हेलिकाप्टर से भामरागढ़ तक गया।

माया : सरकारी तामझाम के रहते असलियत का पता कैसे लगेगा?

जिचकार : मैंने किसी अधिकारी को आने की पूर्व सूचना नहीं दी थी। यह आकस्मिक यात्रा थी, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। यह अवश्य है कि नक्सलियों से भरे इस क्षेत्र में जाते समय हम हथियारों से लैस थे।

माया : शहरी दुनिया और उनमें क्या फर्क लगा?

जिचकार : वही बताने जा रहा हूं। भामरागढ़ तो आदिवासी गांवों का समूह है। वहां माड़िया जनजाति रहती है। माड़िया जनजातियों में वस्त्रों के प्रति लापरवाही है। पुरुष कमर में लंगोटी बांधते हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां कपड़े से एक स्तन ढका रखती हैं। विवाहित महिलाएं वक्ष खुला रखती है। पुरुष दाढ़ी-मूंछ नहीं रखते, परंतु केश सजाते हैं। कपड़े भद्दे नहीं होते। जीवनयापन का तरीका ऐसा है कि वे गांव बदलते रहते हैं। वे बीज फेंककर खेती करते हैं और फसल ठीक नहीं आयी, तो पूरा गांव अन्यत्र बस जाता है। हम जिस गांव को बीनागुंडा मानकर पहुंचे वह नक्शे में, गुंड़ेनहुंडा था। इसी तरह जनगणना भी ठीक से नहीं हुई। शायद कोई गया ही नहीं। ३१ गांवों में कुल २०५ परिवार और १३०० आबादी दर्ज है। जबकि मैंने खुद कुछ गांवों में १०० परिवारों को देखा। डा० प्रकाश आमटे के अस्पताल में बहिर्रोगी विभाग में एक हजार से ज्यादा माड़िया मरीजों के केस-पेपर्स से भी इसकी पुष्टि होती है।

माया : उनकी बीमारी व कुपोषण के लिए प्रशासन कितना जिम्मेदार है?

जिचकार : कुपोषण का कारण उनमें फैला अंधविश्वास भी है। वे मानते हैं कि गाय या भैंस का दूध दुहने से खून निकलेगा। इसलिए दूध वर्जित है। बच्चों में कुपोषण ज्यादा है। वैसे डा० आमटे ने मुझे बताया कि माड़िया शौच के बाद सफाई के लिए पानी का उपयोग नहीं करते, बल्कि पत्थर या सूखी पत्तियों से सफाई करते हैं। इससे नदियों का जल अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं से वे मुक्त हैं तथा पेचिश या दस्त की बीमारी उन्हें नहीं होती। मैंने गांववालों को मीठे अमरूद का टुकड़ा दिया तो, वे गुड़-गुड़ कहकर चिल्लाने लगे तथा अजीब मुंह बनाया जैसे खट्टी चीज आ गयी हो। पता लगा कि उन्होंने बाजार में गुड़ चखा है और मिठास के नाम पर वे उसे ही जानते हैं। इन गांवों की स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन तंत्र को सुधारना जरूरी है। हालत यह है कि वन, आदिवासी विकास और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी अन्य विभाग का अधिकारी इन क्षेत्रों में नहीं गया। यह सही है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या 'आहार' है और यह भी एक तथ्य है कि कृषि विभाग की मशीनरी उन तक नहीं पहुंच सकी है।

माड़िया जनजातियों में वस्त्रों के प्रति लापरवाही है। पुरुष कमर में लंगोटी बांधते हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां कपड़े से एक स्तन ढका रखती हैं। विवाहित महिलाएं वक्ष खुला रखती हैं।

आदिवासियों में 'घोटुल' प्रथा है। गांव के बीच इस सामुदायिक सभागृह की छत पर आदिवासी उप योजना की मेहरबानी से मंगलौरी कवेलू आ गये हैं। यहां शाम को युवक-युवतियां जमा होते हैं और वे विवाह के लिए अपने साथी का चयन करते हैं। शिक्षा-प्रसार के लिए घोटुल को पाठशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु शिक्षकों की कमी और शिक्षा के महत्व को न समझने के कारण विद्यालय ठीक से नहीं चलाये जाते। सातवीं योजना में राज्य के १०६५ आदिवासी गांवों में बिजली पहुंचानी है, परंतु यह तभी होगा, जब युद्ध स्तर पर अभियान छिड़े।

माया : माड़िया जनों के सही विकास के लिए क्या करना उचित है?

जिचकार : जंगलों के संरक्षण के नाम पर वन कर्मचारियों के उत्पीड़न से उन्हें बचाया जाये। ज्यादा-से-ज्यादा जमीन खेती के लिए इस्तेमाल हो तथा खेती का तरीका इन वनवासियों को सिखाया जाये। कम लागत के घर व नलकूपों की व्यवस्था कराना भी जरूरी है।

माया : क्या यह सपना सच होगा?

जिचकार : जानकारी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री ने सड़कों तथा पुलों का निर्माण शुरू कराया। युवा और निष्ठावान अधिकारियों की तलाश शुरू हो चुकी है जो भामरागढ़ के विकास को अपने जीवन का उद्देश्य बनायेंगे। ऐसे लोगों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी होंगी। ■

पैमाने पर कटाई के कारण इमली के इक्के-दुक्के पेड़ ही अब वहां नजर आते हैं। इस क्षेत्र में आरक्षित वन का आधा हिस्सा आदिवासियों के कब्जे में, है। जब वन-अधिकारियों ने उन्हें बेदखल करना चाहा, तो आदिवासी क्रुद्ध हो गये। उन्होंने हमला कर वन विभाग के गार्ड को घटनास्थल पर ही मार डांला।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गढ़चिरोली, ठाणे आदि आदिवासी-बहुल जिलों में वन तथा राजस्व भूमि पर अवैध कब्जों की भारी समस्या है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण रक्षा के लिए कानून बनाया, जिसके कारण वन-भूमि के पट्टे किसी को देना संभव नहीं है। वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन १० वर्ष या ज्यादा समय से आदिवासियों के वास्तविक कब्जे में है। इतने वर्षों से वहां रहने के बाद अब उनकी समझ में नहीं आता कि उन्हें क्यों भगाया जा रहा है?

महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों के गठन के समय १९५६ में झुरमुट जंगल के रिकार्ड की अदला-बदली भी हुई थी। ऐसी १० हजार एकड़ से ज्यादा भूमि सिर्फ कागज पर जंगल है, जबकि वहां सपाट-सूखा मैदान है। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने में विलंब तथा राज्य सरकार के जिला कार्यालयों में सही रिकार्ड के अभाव में इस जमीन का वितरण नहीं हो पा रहा है।

महाराष्ट्र के राजस्व राज्यमंत्री रोहिदास पाटील ने दिल्ली जाकर वन भूमि आदिवासियों को वितरित करने की इजाजत मांगी। श्री पाटील ने 'माया' को बतलाया, "एक बार केंद्र सरकार 'हां' कर दे, तो कम-से-कम एक लाख एकड़ जमीन पर बसे लाखों लोगों का विवाद हल हो जायेगा। इस संबंध में पूरे ब्योरे के साथ प्रस्ताव केंद्र के पास भेजे गये हैं। लेकिन वह खुद भी यह नहीं जानते कि केंद्र कब हामी भरेगा।"

भ्रष्टाचार में इजाफा : ईंधन के लिए लकड़ी कटाई पर वन विभाग द्वारा उत्पीड़न, देशी शराब चुआने पर आबकारी विभाग द्वारा लूट तथा साहूकारों और सरकारी अमले के शोषण कां दुष्परिणाम है कि वे शहरी आदमी पर अब यकीन ही नहीं करते। धुलै, जलगांव और नासिक जिलों तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर वे लूटपाट करने लगे हैं। नर्मदा की परिक्रमा करनेवालों से लेकर राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर जानेवाले ट्रकों तक को लूट लिया जाता है।

भ्रष्ट आदिवासी नेता : महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में इस नाराजगी ने नक्सलवाद का रूप धारण कर लिया है। आदिवासी नेताओं के भ्रष्टाचार तथा शोषण के कारण इनकी ताकत में इजाफा हुआ है। भूतपूर्व आदिवासी मंत्री बाबूराव मड़ावी के विरुद्ध आदिवासियों की सहकारी समिति में लाखों रुपए के घपले के आरोप लगे। शिकायत मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण तक पहुची, परंतु कुछ नहीं हुआ। एक सूत्र के अनुसार श्री मड़ावी मुख्यमंत्री के कृपापात्र हैं। इसी तरह एक भूतपूर्व मंत्री दिलावर सिंह पाड़वी के बारे में विख्यात था कि मुर्गी की टांग पर वह कहीं भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते थे। भू०पू० मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के मंत्रिमंडल में गृहराज्य मंत्री रहे स्वरूप सिंह नाईक भी भ्रष्टाचार की शिकायतों के दायरे में रहे।

सरकारी अफसर व मंत्री तो आदिवासियों के उत्पात के बहाने तथा कुछ अन्य बहाने बनाकर ऐसे

साक्षात्कार/शिवाजी राव मोघे

अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती

महाराष्ट्र के आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं पर 'माया' ने महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री शिवाजी राव मोघे से विस्तार से बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, इस बातचीत के कुछ अंश :

माया : महाराष्ट्र में आदिवासियों की बड़ी संख्या होने के बावजूद सरकार उनके साथ न्याय क्यों नहीं करती?

मोघे : यदि यह मान्यता है, आपकी तो यह गलत तथ्यों पर आधारित है। आदिवासी विकास उपयोजना में पहले कुल योजना खर्च का ४ से ५ प्रतिशत इस उपयोजना के हिस्से आता था। हमने विचार किया कि आदिवासियों की आबादी ९ प्रतिशत से ज्यादा है। इसलिए जून १९८६ में इसे ९ प्रतिशत किया गया, यानी १९८६-८७ में ११३.५० करोड़ और १९८७-८८ में २७२.९७ करोड़ रुपए, यानी १९८५-८६ से दो गुने से भी ज्यादा।

माया : लेकिन आदिवासी उपयोजना का लाभ सिर्फ उन्हें होता है जो अधिसूचित क्षेत्र में रहते हैं और उन पर भी स्वीकृत राशि ठीक ढंग से खर्च नहीं होती?

मोघे : आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दूं कि पिछले दो वर्ष से हमने व्यूह रचना बदलकर उन आदिवासियों को भी लाभ दिया जो अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं रहते। दरअसल, अलग योजना बनायी गयी। १९८७-८८ में १४ करोड़, ५३ लाख रुपए उनके विकास पर खर्च किये गये। यही नहीं, सुधारित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (मोडीफाइड एरिया डेव्लपमेंट एप्रोच अर्थात 'मांडा') योजना में १० हजार आबादीवाले वे इलाके भी शामिल किये गये, जहां ५० प्रतिशत आदिवासी हैं, भले ही ये बस्तियां 'उपयोजना' में शामिल न हों। इस तरह के १८ 'माडा' पाकेट में ५९६ गांवों को लाभ मिला और अब १३ 'माडा' तथा १४ मिनी-माडा पाकेट में ६५८ गांव शामिल किये जा रहे हैं। आपकी इस शिकायत के उत्तर में कि खर्च ठीक ढंग से नहीं होता, इतना बता दूं कि मंत्रियों की अध्यक्षता में निगरानी-समितियां बनी हैं। मैं खुद आदिवासियों के बीच जाकर पूछतांछ करता हूं। सिर्फ नौकरशाही पर विश्वास करने के वजाय जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क करते हैं। जहां शिकायतें मिलीं, हमने तुरंत जांच करायी।

माया : आंकड़ों से भले ही स्थिति प्रभावशाली लगे, परंतु गांवों तक सड़कें नहीं हैं। पाठशालाएं नहीं और न रोजगार के साधन।

मोघे : एक सीमा तक यह सही है कि संपर्क के साधन कम हैं। सीमित स्त्रोतों के बावजूद वन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की मदद से हर मौसम में कारगर पुख्ता रास्ते बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं को भी मदद देते हैं ताकि वे आश्रमशालाएं खोलें। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। पिछले दो वर्ष में २७ आश्रमशालाएं खुली, जिनमें से १८ का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ में है। पिछड़े वर्गों के लिए ६७ छात्रावास खौलने की भी इन संस्थाओं को अनुमति दी गयी।

माया : आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके उत्पादन खरीदने की योजना में कितनी सफलता मिली? क्या सचमुच उससे उन्हें लाभ मिल सका?

मोघे : राज्य के १४ जिलों के ५९ ताल्लुकों में आदिवासी विकास निगम एकाधिकार खरीदी करता है। ज्वार, गेहूं, चावल आदि १४ कृषि उत्पादन तथा गोंद, हर्र, महुवे का फूल जैसी वनोपज की खरीदी से अब आदिवासी साहूकार के शिकंजे से बच जाते हैं। आपको एक बात बतलाऊं। ठाणे जिले में लाखों रुपए की घास व्यापारी मुफ्त या चंद पैसों में खरीद लेते थे। महाराष्ट्र में सूखे के कारण यही घास भारी मुनाफे पर बेची जाती थी। इस बार राज्य सरकार ने सीधे आदिवासियों से घास खरीदी, जिससे ४० हजार मी० टन चारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भेजा जा सका और ४५ हजार आदिवासी परिवारों को बिना अतिरिक्त श्रम के आय का साधन मिल गया। वे शोषण से बचे। केंद्र सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की।

माया : आज भी महाराष्ट्र के आदिवासी जिलों से भुखमरी व बंधुआ मजदूरी की खबरें आती रहती हैं? सरकार इस दिशा में कुछ क्यों नहीं कर पाती?

मोघे : भुखमरी कहना तो ठीक नहीं होगा, परंतु कुपोषण की भारी समस्या है। ग्राम विकास विभाग के माध्यम से आदिवासियों में

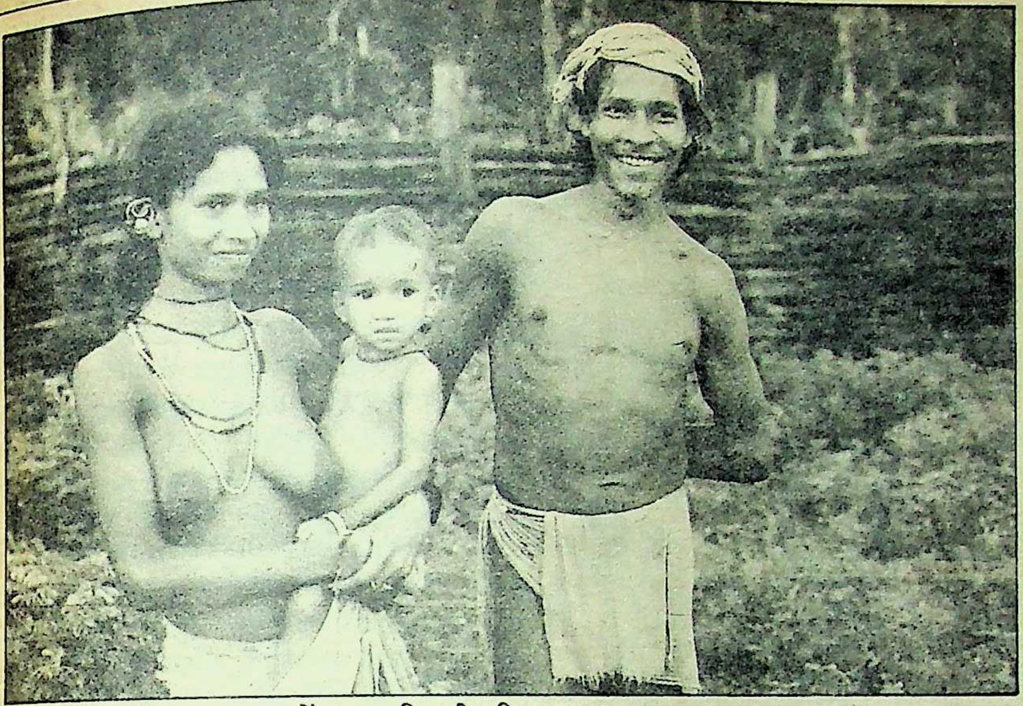

आदिवासी संस्कृति: प्रसन्न मुद्रा में एक आदिवासी परिवार

पोषाहार तथा दूध का वितरण किया जाता है, जबकि आदिवासी विकास विभाग ने दुधारू पशु, मुर्गियां तथा बीज देकर उन्हें स्वस्थ तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की। ठाणे जिले में कुछ स्वयंसेवी संगठनों के जरिए पहली बार बंधुआ मजदूरी की शिकायत मिली। हमने तुरंत कार्रवाही कर उन्हें मुक्त कराया। यही नहीं, सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि फिर से बंधुआ मजदूरों की छानबीन करें।

माया: कई जगह आदिवासियों की जमीन पर गैर-आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है। वन विभाग भी उन्हें बेदखल करता है। इससे उनका रोष नक्सलवाद या हिंसा के अन्य रूपों में फूटता है।

मोघे: जिन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया गया था, उनमें से ९५ प्रतिशत से ज्यादा को पिछले एक साल में जमीन वापस दिलायी गयी। बाकी ५ प्रतिशत का अदालत में मामला चल रहा है। वन और राजस्व विभाग के बीच जमीन के स्वामित्व या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर जमीन खाली कराने के आदेश पर इस समय मेरा टिप्पणी करना अनुचित होगा। इन मामलों में सरकार रास्ता खोज रही है।

माया: आदिवासी नेताओं के कथित भ्रष्टाचार से क्या आदिवासियों की तरक्की पर विपरीत असर पड़ा...

मोघे: (बीच में हस्तक्षेप कर) मैं अपनी ही बात कर सकता हूं। नीति या व्यक्तिगत फैसले में मेरी गलती हो, बताएं। दूसरों पर टिप्पणी करने की मेरी इच्छा नहीं है।

■

दुर्गम क्षेत्रों में दौरा करने जाते ही नहीं हैं। इसीलिए उनकी समस्याओं का उन्हें पता नहीं लग पाता। बाबा आम्टे के बेटे तथा प्रचार से दूर रहनेवाले डा० प्रकाश आम्टे ने आदिवासियों की सेवा के लिएँ हेमलकसा में एक आश्रम बनाया। गहन जंगल में रोगी आदिवासियों को उपचार करने तथा उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ानेवाले डा० प्रकाश नौकरशाही तथा शोषक नेतृत्व की आंख का कांटा बन गये। उन्होंने शाला खोली, तो सरकार ने मान्यता देने में ही टालमटोल की। चार साल बाद मान्यता तब मिली, जब आदिवासी विभाग के वर्तमान मंत्री शिवाजी राव मोघे वहां पहुंचे तथा पूरा किस्सा सुना। (देखिए साक्षात्कार)

शोषण के शिकार: कानून और व्यवस्था की पहुंच से बाहर ये आदिवासी हमेशा स्थानीय भूमिपतियों, साहूकारों तथा ऊंची पहुंचवालों के शोषण के शिकार होते रहे हैं। बंबई के निकट स्थित ठाणे के एक आदिवासी क्षेत्र में वहां के भूमिपति ने इतना आतंक फैला रखा था कि पुलिस भी वहां का रुख नहीं करती थी। उस इलाके की हर जवान आदिवासी महिला शारीरिक शोषण का शिकार हो चुकी थी और दूसरे क्षेत्र के आदिवासी उनका हाथ थामने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। फलत: अधिकाश आदिवासी लड़कियां कुंवारी रह गयीं। सितंबर-अक्तूबर १९८५ में उक्त भूमिपति की कारस्तानी प्रकाश में आयी, लेकिन उसे दबा दिया गया।

२६ अप्रैल, १९८७ को आठ महिला संगठनों के अलावा हिंद मजदूर किसान पंचायत तथा युवा क्रांति के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने शोषित आदिवासी पुरुषों व महिलाओं के साथ जनता पार्टी विधायक मृणाल गोरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री जीवराम महाज्ञन से भेंट क्री और गोसालवाड़ी गांव के एक कुख्यात भूमिपति (धनाजी सेठ) के शोषण की अकथ दास्तान उन्हें सुनायी।

प्रतिनिधि मंडल के साथ आयी आदिवासी काशीबाई ने मंत्री को बतलाया कि धनाजी सेठ उसे दिनदहाड़े उठवाकर ले गया और चार दिनों तक अपने कब्जे में रखकर उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे थाने ले जाकर उसके विरुद्ध उलटे शिकायत दर्ज करा दी गयी कि वह सड़क पर उपद्रव कर रही थी।

काशीबाई की तरह अनेक आदिवासी महिलाएं बलात्कार की शिकार हुईं। प्रतिवाद करनेवाले सुदाम को पुलिस चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले गयी और उसे बिजली के झटके दिये। पुलिस के अनुसार उसे २८ फरवरी, १९८७ को रिहा कर दिया गया, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। धनाजी के आतंक के कारण उस इलाके के कई युवा आदिवासी गांव छोड़कर भाग गये। छह हत्याओं के जुर्म में १५ वर्ष जेल में काटकर आने के बाद धनाजी पुन: सक्रिय हो उठा। आदिवासियों के कल्याण के लिए मधु मोहिते, शांताराम पांधरे तथा नत्थूराम पवार पर घातक हमले किये गये। गृहराज्यमंत्री जीवराम महाजन ने दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने तथा जपा विधायक मृणाल गोरे ने ८-१० दिन के भीतर सरकारी कार्रवाई न होने पर संघर्ष करने का ऐलान किया, लेकिन इस घटना के एक वर्ष बीतने पर भी दोनों पक्षों ने कुछ नहीं किया।

इसी तरह इसी वर्ष महाशिवरात्रि (१६ फरवरी, १९८८) के दिन ठाणे की वाड़ा स्थित आदिवासी आश्रम शाला में घुसकर कुछ शहरी युवकों ने आदिवासी छात्राओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। आरोप है कि इनमें भाजपा और इंका के कुछ नेताओं के बेटे भी शामिल थे। मौके की नाजुकता को भांपकर आदिवासी छात्राओं ने कमरे के दरवाजे भीतर से बंद कर लिये और सांकलें खोलने से इनकार कर दिया, तो नेता-पुत्रों ने दरवाजों पर बाहर की ओर से सांकलें लगा दीं तथा बाहर रखे सामानों की तोड़-फोड़ की। संस्था के सचिव एस०पी० कुलकर्णी ने पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करायी, लेकिन बताया जाता है कि एक सांसद तथा एक प्रभावशाली विधायक के दबाव के कारण पुलिस लाचार रही।

जब महानगर बंबई से ६० से ८० कि०मी० दूर स्थित इन ताल्लुकों-गांवों में आदिवासी महिलाएं शारीरिक शोषण से बच नहीं पातीं और बलात्कारी अपनी पहुंच के कारण खुले घूमते-फिरते आतंक मचाते रहते हैं, तो दुर्गम पहाड़ी इलाकों के आदिवासियों के शोषण की सिर्फ कल्पना भर की जा सकती है, जहां न तो संचार और यातायात व्यवस्था है और न ही सरकारी अमलों की पहुंच।

भूले-बिसरे आदिवासी: १९८१ की जनगणना के हिसाब से महाराष्ट्र में ६ करोड़, २८ लाख आबादी में ५७ लाख ७२ हजार आदिवासी हैं। अर्थात कुल जनसंख्या के ९.१९ प्रतिशत। (सरकारी आकलन के अनुसार अब महाराष्ट्र की

आबादी ७ करोड़ और आदिवासियों की संख्या ६३ लाख से ऊपर पहुंच चुकी है।) इस आंकड़े को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ठाणे, नासिक, धुलै, गढ़चिरौली तथा चंद्रपुर जिलों के ऐसे अनेक देहात हैं, जहां कोई सरकारी अफ़सर जाने का कष्ट ही नहीं उठाना चाहता।

सरकार आदिवासियों के उत्थान पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, परंतु न तो वे पूरी तरह शोषण-मुक्त हो सके और न ही उन्हें सामाजिक न्याय मिल सका। महाराष्ट्र में एक भी आदिवासी सचिव या पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी नहीं बन पाया। सचिवालय में आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारी भी उत्तर पूर्व के आदिवासी हैं। उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय या वरिष्ठ सिविल कोर्ट के न्यायाधीशों में एक भी आदिवासी नहीं है। महाराष्ट्र से उच्चतम न्यायालय में किसी आदिवासी न्यायाधीश की नियुक्ति का सपना पूरा होने में तो शायद पूरी सदी बीत जाये। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नामजद सदस्यों में पिछले १० वर्ष में शायद एंक भी आदिवासी का नाम नहीं आया।

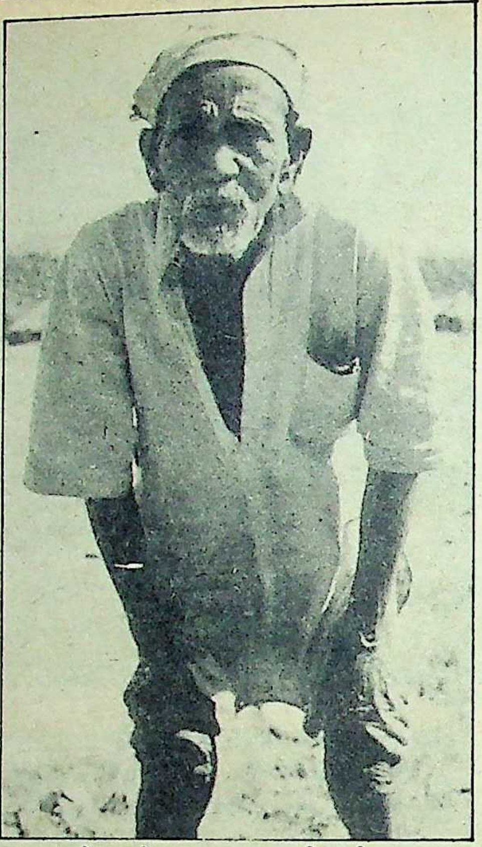

एक अंतहीन प्रतीक्षा : एक वृद्ध आदिवासी

इस समय महाराष्ट्र के रोजगार दफ्तरों में ४० हजार से ज्यादा बेरोजगार आदिवासियों के नाम दर्ज हैं। राज्य में साल में यदि ४ पद उनके लिए आरक्षित हैं, तो मुश्किल से एक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। पहले, दूसरे या तीसरे वर्ग के पद खाली रहें तब तो समझ में आता भी है, परंतु चौथे वर्ग के सैकड़ों पद रिक्त रहने की विडंबना समझ से परे है। अधिकारी एक ही उत्तर देते हैं, "उचित पात्र नहीं मिला।" आदिवासीबहुल नासिक जिले के भिवंडी, मालेगांव नगरपरिषद या नासिक महापालिका में आदिवासी चपरासी के पद तक पर नियुक्त नहीं किये गये। सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए ३३० आश्रम-शालाएं खोल रखी हैं, जहां आदिवासी छात्र तथा शिक्षक रहकर पढ़ और पढ़ा सकें। इनमें से सिर्फ ५६ शालाएं सरकारी इमारतों में चल रही हैं और बाकी किराये के टपरों में।

यों, संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासकीय विवरण राज्यपाल के पास नियमित रूप से भेजा जाये। लेकिन असल में हुआ क्या? ३१ अक्तूबर, १९७५ को जो रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी, उसे ९ अक्तूबर, १९७७ को पेश किया गया। अक्तूबर १९७६ की रिपोर्ट मार्च १९७८ में राज्यपाल को मिली और १९७७ की रिपोर्ट का १९८२ तक पता नहीं था।

गैरआदिवासियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। सरकार ने कानून बनाकर जमीन वापस कराने का बाजे-गाजे के साथ प्रचार किया, लेकिन ३१ मार्च, १९८६ तक की स्थिति इस प्रकार थी—कुल २७ हजार प्रकरणों में से ११ हजार प्रकरणों में आदिवासियों की जमीन वापसी के आदेश हुए, परंतु सिर्फ ९ हजार मामलों पर अमल हो सका। इतना ही नहीं, स्थानीय बड़े लोगों की मिली भगत से कुछ भी हो सकता है। धुलै जिले में वन-अधिकारियों ने १०० से ज्यादा गांव उजाड़ने के बाद कहा, "हमने तो ११ गांव उजाड़े थे, बाकी गांवों के आदिवासी तो डरकर भाग गये।"

—बंबई ब्यूरो

Specially made for Government of India
Super Deluxe
NIRODH
Extra thin coloured
भारत सरकार के लिये निर्मित
सुपर डीलक्स
निरोध
विशेष महीन

अब उपलब्ध है
सुपर डीलक्स निरोध

यह सबसे पतला कन्डोम (0.03 मि.मी.) है। रेशम सा मुलायम चिकनाई-युक्त रंगीन। 100% इलैक्ट्रानिक विधि से जांचा परखा। आधुनिक जापानी टैक्नॉलोजी द्वारा निर्मित।
आपको अत्यधिक स्वाभाविक आभास एवं विश्वसनीयता प्रदान करता है।

सुपर डीलक्स निरोध रु.2 में 4
सर्वोत्तम सुरक्षा का प्रतीक

सब से पतला, मुलायम, सुरक्षित।

davp 87/461

सोन नदी आयोग भंग

किसानों के प्रति सरकार की हमदर्दी का नमूना

जल संसाधन मंत्रालय के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वह १९८० में गठित सोन नदी आयोग को निर्धारित कार्य संपन्न करने के पूर्व ही ३१ मार्च, १९८८ को भंग कर रही है? रोचक तथ्य यह है कि जल संसाधन राज्य मंत्री कृष्णाशाही बिहार की ही हैं, फिर उन्होंने प्रदेश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक तिहाई खाद्यान्न पैदा करनेवाले पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद व रोहतास जिलों के किसानों के हितों को अनदेखा क्यों किया? सोन नदी आयोग के भंग होने से इस क्षेत्र के किसानों को किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा?

केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए काफी दरियादिली दिखायी है, लेकिन जिन नीतियों पर सरकार चल रही है, उससे यह नहीं लगता कि किसानों की हालत सुधारने के लिए वास्तव में सरकार चिंतित है। यह भी हो सकता है कि सरकार की नजर केवल टिकैत-प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ही सीमित हो गयी हो। यदि ऐसा नहीं होता, तो बिहार के सोन नहर के इलाके के किसानों को बरबाद करने का निर्णय सरकार न लेती।

बिहार के पांच अति संवेदनशील जिलों पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद व रोहतास को, जहां की लगभग २१.५ लाख एकड़ भूमि में सोन नहरों से सिंचाई की सहूलियत हासिल थी, अब बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। शायद भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय यही चाहता है। विडंबना यह है कि इस मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री की कुरसी पर बिहार की ही कृष्णा शाही आसीन हैं।

दरअसल, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा १९८० में जिस सोन नदी आयोग का गठन किया गया था, उसे बगैर अपना सारा उद्देश्य पूरा किये ही ३१ मार्च, १९८८ को भंग किये जाने के जल संसाधन मंत्रालय के फैसले ने सोन नहरी क्षेत्र के जागरूक किसानों को बिलकुल सन्न कर दिया है। सोन नदी आयोग का मुख्यालय पटना में ही है। अधूरे आंकड़ों व अधूरी सूचनाओं को संकलित कर आयोग तो ३१ मार्च के पूर्व अपना प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द कर अस्तित्व खो देगा, पर सोन नहरी क्षेत्र की वे तमाम समस्याएं, जिनसे निपटने के लिए इस आयोग का जन्म हुआ था, अब भी बरकरार हैं। इस सरकारी अनीति के खिलाफ 'सोन नहर किसान संघर्ष समिति' के जरिये विरोध तो शुरू है ही, इन क्षेत्रों के विधायक भी बुरी तरह उत्तेजित हैं।

बिहार पर ही चोट : कृष्णा शाही

अधूरे कार्य : इस अल्पजीवी आयोग को कई महत्वपूर्ण कार्य करने थे और कुछेक गंभीर विवाद भी दूर करने थे। मसलन, सिंचाई व बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के वास्ते सोन के जल के उचित समय पर अधिकाधिक उपयोग हेतु सोन बेसिन में बृहद योजना तय करना, साथ ही पूरे क्षेत्र में जल उपलब्धता की सही जानकारी हासिल करना था। सोन बेसिन में गंगा नदी के पानी के इस्तेमाल की संभावनाओं के बारे में योजना बनाने के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण कार्य आयोग के जिम्मे थे। उ०प्र०, बिहार व म०प्र० के बीच हुए बाण सागर समझौते से उपजे विवादों का हल निकालना और जल तथा भूमि संसाधन की बेहतरी के लिए नयी परियोजनाओं का अनुपूरक अन्वेषण करके प्रतिवेदन देने का काम भी उसके जिम्मे था। लेकिन इनमें से एक भी कार्य को आयोग अंजाम नहीं दे सका।

गौरतलब बात यह है कि बिहार के पांच प्रमुख जिलों में सोन नहरों के लिए जल की प्राप्ति बहुत हद तक उ०प्र व म०प्र० के इलाके से उपलब्ध जल की मात्रा पर ही आश्रित है। आयोग ने जिन ११ परियोजनाओं को सोन बेसिन में अंकित किया है, उनमें सिर्फ एक कदवन ही बिहार में पड़ती है। इसलिए इनके नियंत्रण की नीति का भी तय होना आवश्यक था। वरना बिहार में सोन नदी के लिए कई मुश्किलें पेश आ सकती हैं। आयोग ने यह अध्ययन भी किया है कि 'केंद्रीय जल आयोग' के सहयोग से तमाम जलाशयों के जल का कैसे सुव्यवस्थित ढंग से सदुपयोग हो। फिलहाल, "सोन नदी आयोग' के अतिरिक्त कोई और एजेंसी नहीं, जिसके जरिये यह कार्य संपन्न हो"—कहते हैं सोन नहरी क्षेत्र के तमाम विधायक।

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत

ASPRO
draws out pain faster

सरदर्द का
बेहतरीन
उपचार

दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा

daCunha/AS/41/87 HIN

Gurukul Kangri Collection Haridwar

अभी मार्च के दूसरे सप्ताह में 'सोन नहर किसान संघर्ष समिति' के संचालक सरयू राय सहित सोन नहरी क्षेत्र के अधिकांश विधायक, जल संसाधन मंत्री कृष्णा शाही के पास इसी मसले को लेकर दिल्ली पहुंचे भी थे और विरोधस्वरूप अपना प्रतिवेदन भी दिया, पर हुआ कुछ भी नहीं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत कर 'जल संसाधन परिषद' की जब स्थापना की थी, तो उसकी सराहना भी काफी हुई थी। पर 'जल संसाधन परिषद' भी कारगर साबित नहीं हो सकी। सोन नहरी क्षेत्र के विधायकों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बिहार का सोन नदी इलाका, चूंकि सोन बेसिन में सबसे नीचे पड़ता है, इसलिए बिहार के किसान वैसे ही तबाह रहते आये हैं। उ०प्र०, बिहार व म०प्र० के बीच १९७३ में हुआ बाण सागर समझौता भी बिहार के सोन नहरी क्षेत्र के किसानों के लिए एक स्थायी सिरदर्द है। दरअसल विगत ११५ वर्षों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के किसान सोन-जल का सिंचाई में सर्वाधिक उपयोग करते रहे हैं। इस तरह सोन-जल पर बिहार के किसानों का 'चिर उपभोगाधिकार' रहा। लेकिन 'वाण सागर समझौता' इसमें बाधा बन गया। उ०प्र० द्वारा पानी रोक लिए जाने से नहरों के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। नतीजतन प्रति वर्ष रबी और खरीफ की फसलें मारी जाती रही हैं। 'सोन नदी आयोग' से बिहार के किसान उम्मीद बांधे बैठे थे कि इस परेशानी का हल आयोग निकाल देगा। पर अब वह उम्मीद खतम हो गयी है।

पृष्ठभूमि : सोन नहरें बिहार में कृषि की रीढ़ हैं। इन नहरों के निर्माण में सबसे अहम भूमिका कर्नल डिकेंस नामक एक अंगरेज अधिकारी ने निभायी थी। कर्नल डिकेंस ने ही १८५३ में यह योजना तैयार की थी कि सोन के जल को कैमूर पर्वतमाला के कई हिस्सों में संकलित कर सिंचाई की व्यवस्था कई जिलों में सुलभ करायी जाये। इस योजना ने तत्कालीन ब्रिटिश शासकों को काफी प्रभावित किया और कर्नल डिकेंस को विस्तृत योजना और संभावित व्यय का ब्यौरा देने को कहा गया। आखिरकार १८६७ में इस योजना को मंजूरी मिल गयी। योजनानुसार रोहतास जिले में डिहरी के निकट सोन नदी पार ८ फुट ऊंचा और १२.५ हजार फुट लंबा एनीकट का निर्माण और सोन के दोनों ओर तीन बड़ी नहरों की खुदाई का काम भी आरंभ हो गया। उस समय दो करोड़ अड़सठ लाख के खर्चे से सात वर्षों में यह कार्य पूरा हुआ था। १८७४ में इन नहरों के जरिये बाकायदा सिंचाई होने लगी, साथ ही नौका परिवहन और मछली पालन का भी कार्य शुरू हो गया। वस्तुतः अंगरेज शासकों का उद्देश्य सोन नहरों के निर्माण के पीछे सिंचाई का कम, परिवहन का ज्यादा था। जिस समय सोन नहर की योजना कर्नल डिकेंस के मन में उपजी थी, उस समय कैमूर पर्वतमाला से लेकर गंगा नदी के बीच के क्षेत्र में सघन जंगल था। इन जंगलों में ही वीर कुंअर सिंह के नेतृत्व में लड़ने वाले सेनानियों की शरणस्थली थी। इस लिहाज से भी सोन का इलाका अंगरेजो के लिए चिंता का विषय था।

सोन नहर प्रणाली की बहु-उद्देशीय योजना के पीछे अन्य बातों के अतिरिक्त सोन क्षेत्र के बागियों को रोजगार मुहैया कर शांत करने का भी इरादा अंगरेज शासकों का था।

सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद पर जब उ०प्र० सरकार द्वारा विद्युत निर्माण के लिए जलाशय का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, तो बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि इससे बिहार में सोन नहरों को मिलने वाले पानी में रुकावट होती। विशेषकर रबी और खरीफ फसलों को सिंचाई के लिए अपेक्षित जल नहीं मिल पाता। बिहार सरकार यह आपत्ति वापस लेने को तभी तैयार हुई, जब रिहंद पर बिजली परियोजना प्रतिवेदन के उपबंधों का हवाला देते हुए आश्वस्त किया गया कि सोन नहरों के लिए जलापूर्ति बनाये रखने के लिए रिहंद जलाशय से ६००० क्यूसेक जल का बहाव निरंतर बनाये रखा जायेगा। लिहाजा विद्युत निर्माण के लिए बेसलोड यूनिट की स्थापना की गयी। इसके पश्चात सोन के जल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए बिहार के रोहतास जिले में डिहरी के समीप इंद्रपुरी में बिहार सरकार द्वारा बराज बनाया गया। पर इसके बावजूद नहरों के आखिरी छोर वाले क्षेत्र तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की क्षमता विकसित नहीं की जा सकी। इसी बीच म०प्र० में बाण सागर के निकट—सोन की मुख्य धारा को बांधकर एक जलाशय निर्माण की योजना बनी। इसके साथ ही सोन की लगभग सभी सहायक नदियों पर विद्युत निर्माण व सिंचाई के लिए योजनाओं पर काम शुरू हो गया। पर इससे सोन के जल को लेकर बिहार, उ०प्र० व म०प्र० के बीच कई तरह की परेशानियां उठ खड़ी हुईं। आखिरकार १६ सितंबर, १९७३ को इन तीनों प्रांतों के बीच एक समझौता हुआ; जिसे बाण सागर समझौते के नाम से जानते हैं। इसी समझौते से यह आंका गया कि सोन में औसतन वार्षिक जलोपलब्धि १४२.५ लाख एकड़ फुट है। इसमें से बिहार को ७७.५ लाख एकड़ फुट, उ०प्र० को १२.५ लाख एकड़ फुट और म०प्र० को ५२.५ लाख एकड़ फुट जल आवंटन की बात तय हुई थी। समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि बिहार में सोन की पुरानी नहरों में ५० लाख एकड़ फुट जलापूर्ति प्राथमिकता के आधार पर बनी रहेगी। समझौते के अनुसार बिहार को मिलने वाले ७७.५ लाख एकड़ फुट तक की जलापूर्ति में १० लाख एकड़ फुट पानी बिहार को बाण सागर जलाशय से और बाकी ६७.५ लाख एकड़ फुट जल सोन की मुख्य धारा और अन्य सहायक नदियों से मिलना था, जिसमें रिहंद भी शामिल था। रिहंद में औसतन वर्ष भर में जल का प्रवाह ३०-४० लाख एकड़ फुट है। किसी-किसी वर्ष यह घटकर आधा भी हो जाता है। लेकिन सोन नहरी क्षेत्र के विधायकों के मुताबिक पिछले दस वर्षों से भी अधिक से समझौते के मुताबिक बिहार को रिहंद से जल नहीं मिल रहा है।

> अधूरे आंकड़ों व अधूरी सूचनाओं को संकलित कर आयोग तो ३१ मार्च के पूर्व अपना प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द कर अस्तित्व खो देगा, पर सोन नहरी क्षेत्र की वे तमाम समस्याएं, जिनसे निपटने के लिए इस आयोग का जन्म हुआ था, अब भी बरकरार हैं। इस सरकारी अनीति के खिलाफ 'सोन नहर किसान संघर्ष समिति' के जरिये विरोध तो शुरू है ही, इन क्षेत्रों के विधायक भी बुरी तरह उत्तेजित हैं।

'सोन नहर किसान संघर्ष समिति' के संचालक सरयू राय कहते हैं, "समझौते के इस खुले उल्लंघन को बिहार के सोन नहरी क्षेत्र के किसान कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। सरयू के मुताबिक १९६६-६७ के भीषण अकाल में बिहार को रिहंद से ६८.६७ लाख एकड़ फुट जल मिला था, तो उस समय किसानों की जान बची थी। पर अब अरसे से समझौते के बावजूद रिहंद का जल बिहार को न मिलना घातक साबित हो रहा है। ऐसी हालत तो तब है, जबकि बाण सागर परियोजना का कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो सका है। बाण सागर परियोजना संपन्न हो जाने पर सोन की मुख्य धारा का प्रवाह भी शिथिल पड़ जायेगा और बिहार के किसान टूट जायेंगे।"

बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा सोन नहरी क्षेत्र से ही आता है। ऐसी स्थिति में सोन नहरी क्षेत्र के किसानों की बदहाली गहरी चिंता का विषय है। सोन नहरी क्षेत्र के तमाम विधायकों ने अभी मार्च के मध्य में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को दिये गये अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बाण सागर समझौता बिहार के लिए अहितकर साबित हो रहा है, इसका तत्काल कोई हल निकाला जाये। पर केंद्रीय जल ससाधन मंत्रालय इन समस्याओं के निराकरण के बजाय ३१ मार्च को 'सोन नदी आयोग' को ही भंग करने जा रही है।

—पटना ब्यूरो

अर्जुन सिंह

बदलते तेवर

अर्जुन सिंह ने अपनी जड़ें जमाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अपने विश्वसनीय लोगों को जमाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, अपने पुत्र अजय सिंह के रास्ते को भी वह निष्कंटक बनाने में लग गये हैं। अर्जुन सिंह किन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं और ऐसा करने के पीछे उनकी दृष्टि क्या है?

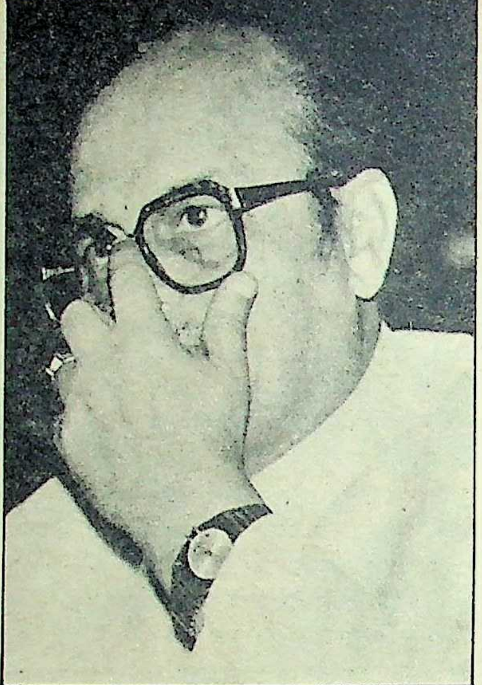

दूरदृष्टि: अर्जुन सिंह

"साहब इन दिनों 'एग्रेसिव' मूड में हैं"—मुख्यमत्री अर्जुन सिंह के बारे में उनके एक नजदीकी सिपहसालार का यह कथन सोलह आने सही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अर्जुन सिंह के आक्रामक तेवर का पहला परिचय सहयोगी मंत्रियों की टीम के चुनाव में ही मिल गया था। अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने वक्त की नजाकत के मुताबिक अपनों और परायों के पर समान रूप से कतरे थे। किंतु इस बार मंत्रियों के चयन में एंकमात्र बालेंदु शुक्ल को छोड़ कर शेष सभी निष्ठा की कसौटी पर जांचे-परखे लोग हैं। सिंधिया खेमे के दूसरे मंत्री शिव प्रताप सिंह का पहले पत्ता काटकर और फिर उनके पुत्र के कथित बलात्कार प्रकरण की जांच करने वाले पुलिस अफसर को निलंबित कर पांसा इस चतुराई से फेंका गया है कि सिंधिया गुट को प्रदेश में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अपने राजनीतिक अभियान का श्रीगणेश छत्तीसगढ़ या विंध्य के बजाय भिंड से करने तथा चंबल विकास प्राधिकरण के गठन से स्पष्ट है कि अर्जुन सिंह ग्वालियर समेत चंबल के इलाके में पांव जमाने और सिंधिया का कद घटाने की अपने अनुयायियों की मुहिम को हरी झंडी दे चुके हैं। भिंड के रौन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक रमाशंकर सिंह को बेतरह तरजीह देने और चंबल विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ग्वालियर के बजाय भिंड में रखने से उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। दाऊ हनुमंत सिंह को सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंप कर मंत्री बनाना दूरगामी परिणामों पर केंद्रित इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वह मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष सांसद महेंद्र सिंह और निर्यात निगम के मनोहर बैरागी जैसे सिंधिया प्रिय लोगों को छेड़ेंगे, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि वह मध्य भारत में अपनी जड़ें जमाने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेंगे। येनकेन प्रकारेण अपनों को उपकृत करना अर्जुन सिंह की चिरपरिचित प्रवृत्ति है। किंतु पहले उनमें औरों का लिहाज करने की प्रवृत्ति थी। संभव है कि यह लिहाज राजनीतिक विवशता की कोख से जनमा हो, किंतु टीम के चयन में इस बार इस लिहाज का लुप्त हो जाना दो बातों की ओर संकेत करता है। पहला यह कि सत्तारूढ़ दल में उनका एक छत्र साम्राज्य है, दूसरे-संदिग्ध निष्ठा वाले लोगों को मौका देकर वह अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए किसी तरह की कोई बला नहीं पालना चाहते हैं।

दुर्गादास सूर्यवंशी, डा० कन्हैयां लाल शर्मा, रसूल अहमद सिद्दीकी, चित्रकांत जायसवाल, राम किशोर शुक्ला आदि का पत्ता काटकर वह अपने इरादों का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने मंत्रि-परिषद में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं दी है जो पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के 'काकस' का सदस्य रहा हो। राजनीतिक क्षेत्रों में फिलहाल इस बारे में काफी कौतूहल है कि कुंवर साहब वोरा के बनाये चेयरमैनों, मसलन—माणक अग्रवाल, शकरलाल ताम्रकार, राजेंद्र भटनागर, मेबेल टिबेलो और किशन पत आदि के साथ क्या सुलूक करते हैं? माना यह जा रहा है कि हिट लिस्ट काफी लंबी होगी और उसमें नेताओं के साथ-साथ मुख्य सचिव आचार्य समेत अनेक अफसरों का भी समावेश है। आधिकारिक स्तर पर फेरबदल की शुरुआत वह भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक बिराज कृष्ण मुखर्जी को एम० नटराजन के स्थान पर पुनः लाकर कर चुके हैं। पूर्व मुख्य सचिव ब्रह्म स्वरूप को इसी क्रम में ऐन सेवानिवृत्ति के दिन नर्मदा घाटी विकास योजना का अध्यक्ष बनाया गया है।

अपनों के प्रति उदारता: विरोधियों को शनैः शनैः शक्तिहीन करने के साथ-साथ अपनों को उपकृत करने का अभियान भी बाकायदा प्रारंभ हो चुका है। सांसद सुभाष यादव को कृषक आयोग का अध्यक्ष बनाना इसी अभियान का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह को प्रदेश इंकाध्यक्ष के पद से हटाये जाने की स्थिति में सुभाष यादव अर्जुन खेमे की ओर से इस पद के दावेदारों में एक थे। किंतु संगठन का मुखिया चंदूलाल चंद्राकर को बनाये जाने के बाद उन्हें कृषक आयोग के गठन की घोषणा कर उसका अध्यक्ष बना दिया गया। कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त सुभाष यादव खेतीबाडी और सहकारिता आंदोलन से सीधे जुड़े होने के कारण इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार थे। किंतु उनकी यह अतिरिक्त खूबी थी कि उनके नेतृत्व में सहकारिता का खेमा तमाम अवरोधों के बावजूद कुंवर साहब के प्रति निष्ठावान बना रहा। कहना न होगा कि उनकी यही खूबी इस महत्वपूर्ण आयोग का अध्यक्ष बनने का बायस बनी। आयोग के गठन को एक ऐसे प्रदेश में जहां नब्बे प्रतिशत आबादी गांव में रहती है, किसानों का दिल जीतने का उपक्रम कहा जा सकता है। यह एक ऐसा उपक्रम था जिसकी प्रशंसा औरों के साथ-साथ माधवराव सिंधिया ने भी मुक्त कंठ से की। इस उपाय से यह भी संकेत मिलता है कि चुनावी लड़ाई में इंका शहरी वोटों के बजाय ग्रामीण मतों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। किसानों को लुभाने और गांवों में असर जमाने के पीछे प्रयोजन यह भी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की दस्तकें अनसुनी रहें और उनका प्रभाव न हो।

भविष्य की तैयारी: अजय सिंह उर्फ राहुल

सत्ता और संगठन में शीर्ष परिवर्तन और बाद के घटनाक्रम में सर्वाधिक घाटे का शिकार

अगर कोई रहा है, तो वह हैं सासंद दिग्विजय सिंह। मुख्यमंत्री पद से मोतीलाल वोरा की विदाई के बाद दिग्विजय सिंह के प्रदेश इंकाध्यक्ष बने रहने की स्थिति में सत्ता और संगठन में अद्भुत और अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिल सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री का समधी और राजपूत होना राजा साहब के आड़े आ गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के एवज में वोरा को केंद्र में स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री का पद मिला, मगर दिग्विजय सिंह लाभ हानि के लिहाज से न घर के रहे, न घाट के। एक समय था कि खुशमिजाज, योग्य और प्रशासनिक क्षमता के धनी दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन तीन साल के अंतराल में फर्क यह आया है कि अर्जुन सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र राहुल (अजय सिंह) उभर कर आये हैं और समधी दिग्विजय सिंह हाशिये में चले गये हैं। इस समय अर्जुन गुट की रणनीति का सूत्र संचालन भी अजय सिंह के ही हाथों में है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारत सिंह को गृह और यातायात जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिलने और राजमणी पटेल, दाऊ हनुमंत सिंह और रामजी महाजन के मंत्री बनने में नेपथ्य में सबसे अहम भूमिका राहुल ने निभायी है। इसके अलावा यदि अर्जुन शिविर की आंतरिक स्थिति पर दृष्टिपात करें, तो वे लोग अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं जो राहुल से सीधे जुड़े हुए हैं या राहुल की पसंद हैं। हालत यह है कि उत्तराधिकारी से संबंधों के आगे कुछ लोगों की पिता के प्रति बरसों की निष्ठा कमजोर पड़ने लगी है। कोई आश्चर्य नही यदि यह स्थिति आगे चल कर शिविर के भीतर द्वंद्व का रूप ले ले।

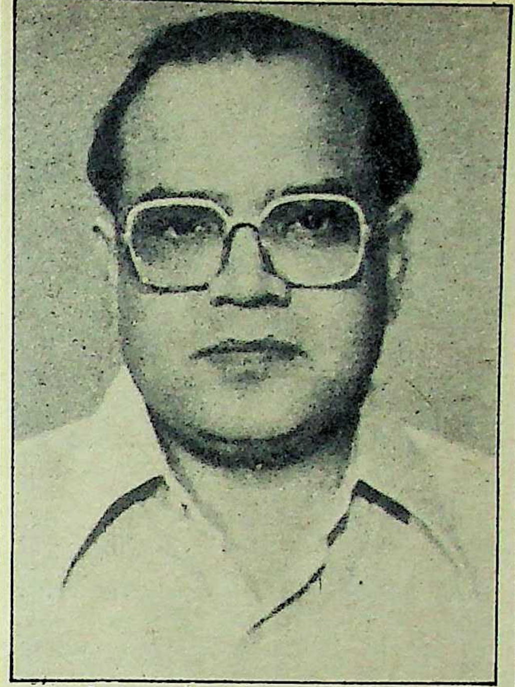

वफादारी रंग लायी: ब्रह्मस्वरूप

पुनर्स्थापित: बिराज कृष्ण मुखर्जी

> **विरोधियों को शनैः-शनैः शक्तिहीन करने के साथ-साथ अपनों को उपकृत करने का अभियान भी बाकायदा प्रारंभ हो चुका है। सांसद सुभाष यादव को कृषक आयोग का अध्यक्ष बनाना इसी अभियान का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह को प्रदेश इंकाध्यक्ष के पद से हटाये जाने की स्थिति में सुभाष यादव अर्जुन खेमे की ओर से इस पद के दावेदारों में एक थे। किंतु संगठन का मुखिया चंदूलाल चंद्राकर को बनाये जाने के बाद उन्हें कृषक आयोग के गठन की घोषणा कर उसका अध्यक्ष बना दिया गया।**

वैकल्पिक पद का पुरस्कार: सुभाष यादव

अब खरसिया: अपनी परंपरागत सीट चुरहट के बजाय छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खरसिया से चुनाव लड़ने की घोषणा अजय सिंह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के अर्जुन सिंह के फैसले से सीधे जुड़ी हुई है। स्पष्ट है कि चुरहट से चुनाव लड़कर पुत्र के राजनीतिक भविष्य को वह झमेले में नहीं डालना चाहते। इंका विधायक दल में शताधिक लोग ऐसे हैं जो संकेत या आभास मिलने पर तत्काल इस्तीफा दे सकते थे। एक कयास यह भी था कि वह फिर से चुरहट से चुनाव लड़ेंगे, मगर कृषि उद्योग विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पटेल के इस्तीफे और अर्जुन सिंह की स्वीकारोक्ति के बाद यह निश्चित हो गया कि वह चुरहट का प्रतिनिधित्व अपने बेटे के लिए छोड़कर आदिवासी बहुल खरसिया से चुनाव लड़ेंगे। आंचलिक विभेदों से परे चुरहट और खरसिया में साम्य यह है कि दोनों ही स्थानों पर सामंती तत्वों का वर्चस्व है। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा नरेशचंद्र सिंह ने कभी इसी सीट से चुनाव लड़ा था। राजघराने का आज भी यहां खासा वर्चस्व है। राजघराने की दो बहनों में एक कुमारी पुष्पा सिंह यहां से सांसद हैं और दूसरी श्रीमती कमला सिंह राज्य सरकार में पृथक आगम मंत्री। रायगढ़ जिले में माना जाता है कि ठाकुर बंधुओं-पृथ्वीपाल सिंह और जगतपाल सिंह पर अर्जुन सिंह का वरदहस्त है और इनमें से जगतपाल सिंह विवादास्पद होने और आंतरिक विरोध के बावजूद अर्जुन सिंह की कृपा से राज्यसभा में पहुंचे हैं। दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने के बाद यह कहना निराधार है कि अर्जुन सिंह खरसिया से चुनाव लड़कर प्रदेश के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं। सचाई यह है कि अर्जुनसिंह प्रदेश में सर्वमान्य और सर्वाधिक शक्तिशाली नेता के रूप में पिछले चुनाव में ही उभर आये थे। इस समय उन्हें चुनौती देने वाला नेता खोजना मुश्किल है। हां, यह जरूर है कि अपार शक्ति व लोकप्रियता के बावजूद उन्होंने अत्यंत सुरक्षित, एक तरह से देखा जाये, तो 'सुरक्षित कांग्रेसी मांद'. का चयन किया है। यहां के मतदाताओं ने सन '७७ की जनता लहर में भी कांग्रेस को २० हजार से अधिक वोटों से जिताया था। सन'८० और '८५ में लक्ष्मी प्रसाद पटेल यहां से क्रमशः २७ और २१ हजार मतों से विजयी हुए थे। अनुमान है कि अर्जुन सिंह की जीत यहां से मतों के विशाल अंतर से होगी और इस जीत के बल पर वह आलाकमान के समक्ष यह दावा करने में चूकेंगे नहीं कि प्रदेश में भाजपा और शुक्ल बंधुओं की कथित जागीर (छत्तीसगढ़) में विद्याचरण शुक्ल के जनमोर्चा का कोई प्रभाव व चुनौती नहीं है।

—सुधीर सक्सेना

अर्जुन सिंह अब बंधे हाथ नहीं

अब जातिगत राजनीति: अर्जुन सिंह

सन '८० से '८५ के दरम्यान अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री जरूर रहे और दिनोदिन शक्तिशाली भी होते गये, लेकिन तब उनके हाथ बंधे हुए थे। इसका एक कारण तो यह था कि विद्याचरण शुक्ल और प्रकाश चंद सेठी तब काफी ताकतवर थे, दूसरे श्रीमती इंदिरा गांधी की 'चेक ऐंड बैलेंस' की नीति अर्जुन सिंह को मजबूत इरादों के बावजूद खुल कर खेलने नहीं देती थी। इसके अलावा तब हर इलाके में ऐसे दो-चार दमदार नेता मौजूद थे, जिनकी श्रीमती इंदिरा गांधी तक सीधे पहुच थी। यह आज भी माना जाता है कि यदि श्रीमती गांधी जीवित रहतीं, तो कृष्णपाल सिंह, श्रीनिवास तिवारी, डा० टुमनलाल, डा० भंवर सिंह पोर्ते आदि अर्जुन सिंह के विरोध के बावजूद टिकट ले आते। मगर कल और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। अर्जुन सिंह के हाथ आज बंधे हुए नहीं हैं और वह चुनावी सफलता को मद्दे नजर रखकर कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्र नजर आते हैं। जाहिर है कि आलाकमान उनके कदमों और कामों का आकलन अंततः चुनाव में हार-जीत के पैमाने से करेंगे।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाना आलाकमान का एक विशुद्ध राजनीतिक निर्णय है। सातवें दशक में राजमाता सिंधिया के सहयोग से लौह-पुरुष पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का तख्ता पलटने वाले गोविंद नारायण सिंह ने काफी समय से अर्जुन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने गत वर्ष प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस आशय की एक लंबी चिट्ठी लिखी थी कि नेताओं के घोटालों और राजे-रजवाड़ों ने प्रदेश में कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर दी है। बाद में वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री से अकेले में करीब आधे घंटे बातचीत भी की। अर्जुन सिंह ने स्वयं तो मुख्यमंत्री रह चुके अपने क्षेत्र के इस वरिष्ठ नेता की चिट्ठी और यत्र-तत्र फब्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की, किंतु प्रदेश इंका के उनके चहेते महामंत्री ललित श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री को लंबी-चौड़ी चिट्ठी लिखकर गोविंद नारायण के आरोपों का सविस्तार उत्तर दिया था। बिहार का राज्यपाल बनाये जाने से गोविंद नारायण सिंह प्रदेश से तो दूर चले गये हैं, लेकिन लंबे अज्ञातवास के बाद इससे उनकी शक्ति और सम्मान में वृद्धि हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उनके पुत्र हर्ष सिंह रामपुर बघेलान से विधायक हैं। गोविंद नारायण सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाने का दिल्ली दरबार का निर्णय इस लिहाज से अर्जुन सिंह के लिए लाभकारी व अनुकूल कहा जायेगा।

फिलहाल यदि अर्जुन सिंह की नजरों में खटकने वाली कोई इकाई है, तो वह है कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम। फोरम की बागडोर विंध्य के ही नेता व पूर्व विधि मंत्री कृष्ण पाल सिंह के हाथों में है। कृष्ण पाल सिंह प्रदेश के उन प्रमुख गिने-चुने नेताओं में एक हैं जिन्हें दिल्ली दरबार के हाथों राजनीतिक पुनर्वास की प्रतीक्षा है। मोतीलाल वोरा के मुख्यमंत्री रहते वह प्रदेश इंकाध्यक्ष पद के ताकतवर दावेदार थे। यह पद हाथ से फिसल जाने के बाद उनके समक्ष राज्य-सभा के लिए लाबीइंग करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मगर उनके इस अभियान में आज उनके सबसे प्रबल विरोधी अर्जुन सिंह हैं।

उपलब्ध सूचना और संकेतों से ऐसा लगता है कि अर्जुन सिंह ने चुनाव में जातीय राजनीति की गोटियां खेलने का फैसला किया है। उनकी नजर मुख्यतः आदिवासी और पिछड़े वर्ग के वोटों पर है। पहले भी उनकी छवि सर्वहारा के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध नेता के तौर पर निर्मित व प्रचारित की गयी थी। खरसिया में लगभग चालीस फीसदी आदिवासी मतदाता हैं। खरसिया से चुनाव लड़कर अर्जुन सिंह एक तो अपनी इस घोषणा पर अमल करेंगे कि वह पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। दूसरे, जीत की स्थिति में प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि राज्य विधानसभा में पिता-पुत्र की जोड़ी एक साथ बिराजेगी।

—सुधीर सक्सेना

बीटीवीटीसी

विकलांगों पर नौकरशाही का नजला

यदि हालात यही रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब भोपाल 'स्वयसेवी संस्थाओं की कब्रगाह' कहलाने लगेगा। वजह यह है कि जब कोई संस्था दीन-दुखियों की सहायता या कल्याण का काम शुरू करती है, तो उस पर सरकार का नजला गिरने में देर नहीं लगती। संगठन की पीठ पर किसी बड़े राजनेता या आला अफसर का हाथ हो, तो बात अलग है, अन्यथा लोगों का भला करने की नीयत वाले संगठनों और लोगों के लिए काम करना दिनोदिन मुश्किल होता जा रहा है। भोपाल में विकलांगों—मुख्यतः अंधों और मूक बधिरों के प्रशिक्षण के लिए गठित संस्था भोपाल टेक्निकल ऐंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (बीटीवीटीसी) के जनमते ही कुछ माह में दम तोड़ देने की कहानी इन्हीं बातों को उजागर करती है।

भोपाल के शहरी इलाके के बाहर लाल घाटी के समीप सुरम्य रिजवान बाग में १६ जून, १९८६ को प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हुआ, जिसमें २३ विकलांगो ने प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। विकलांगों को प्रशिक्षण देने के लिए अमरीका के एरीजोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का विशेष तौर पर भोपाल आगमन हुआ। ओरीज़ाना विश्वविद्यालय में दूसरी बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है और यहां विकलांगों के लिए एक सर्वथा पृथक संकाय है। इस विश्वविद्यालय के विजय सिंह और संकाय के डीन डा० विलियम लुई १९८५ में भारत आये और उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधिमंत्री मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भेंट और चर्चा की। यह इन्हीं मुलाकातों का नतीजा था कि भोपाल में बीटीवीटीसी की नींव पड़ी। इस संस्था के प्रबंध संचालक का दायित्व संभाला श्रीमती आयंगर ने। उन्होंने रिजवान बाग में एक लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से जगह ली और प्रशिक्षण केंद्र के लिए कुछ शेडों का निर्माण किया। इस बीच सोलह जून

को ओरीजाना विश्वविद्यालय से करीब १६ लाख रुपए की पहली किस्त संस्था को प्राप्त हुई और प्रशिक्षण केंद्र में अंधों गूंगों बहरों आदि के प्रशिक्षण का काम जोर-शोर से चल पड़ा। प्रशिक्षणार्थियों में काफी लोग गैस पीड़ित भी थे तथा गैस पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए शासन की योजनाएं इन दिनो अलग से भी चल रही थीं। इनके क्रियान्वयन का दायित्व अतिरिक्त सचिव, गैस राहत एवं पुनर्वास डा० ईश्वर दास के कंधों पर था। सरकारी अमले ने गैस पीड़ितों के पुनर्वास व कल्याण के लिए कितनी ईमानदारी से कितना काम किया, यह इस लेख का विषय नहीं है, लेकिन इस कथा के संदर्भ में यह सच है कि उक्त गैरसरकारी संस्था की सक्रियता और सफलता डा० ईश्वरदास की आंखों में किरकिरी की तरह खटकने लगी। डा० ईश्वरदास ने २८ जून को संस्था को संदिग्ध करार देते हुए एक पत्र केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा, जिसकी प्रतियां उन्होंने गृह सचिव, आंतरिक सुरक्षा मंत्री, अमरीका में भारत के राजदूत और केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजी। पत्र में उन्होंने यह मंतव्य व्यक्त किया कि यूनियन कार्बाइड और अमरीकी खुफिया संगठन सीआईए भिन्न-भिन्न संगठनों के जरिए गैस पीड़ितों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं और इनका अंतिम प्रयोजन गैस पीड़ितों के आक्रोश को सरकार की ओर मोड़ना है। ये इस मकसद से सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, जिनके आधार पर भविष्य में गैस त्रासदी को तोड़-फोड़ का नतीजा सिद्ध किया जा सके। जानकार सूत्रों के अनुसार डा० ईश्वरदास के पत्र में बीटीवीटीसी के अलावा भोपाल ग्रुप फार इंफारमेशन ऐंड एक्शन और आगापे का भी उल्लेख था। समझा जाता है कि सरकारी अफसरों की लाबी ने आगापे को रेडक्रास के लिए खतरे के तौर पर देखा। मध्य प्रदेश शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस पत्र पर उच्च स्तर पर तत्काल कार्यवाही हुई। फौरी कार्यवाही के तहत २६ जुलाई को संस्था की रकम 'फ्रीज' कर दी गयी और प्रशिक्षण में सहायता के लिए अमरीका से भारत आने वाले प्रोफेसर का वीजा रद्द कर दिया गया। इसी क्रम में श्रीमती आयंगर पर फेरा के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया, जबकि उन पर फेरा के प्रावधान लागू ही नहीं होते, क्योंकि कोई भी गैरव्यावसायी संस्था पर विदेशी मुद्राविनिमय कानून लागू ही नहीं होता। संस्था के प्रशिक्षण केंद्र पर कुठाराघात करने के अभियान में नौकरशाही के सहभागी बने एक बड़े घराने के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक के भोपाल स्थित संवाददाता, जिनकी पत्नी को उक्त संस्थान में ही जरूरत न होते हुए भी नियमित वेतन पर नौकरी दी गयी थी। नौकरशाही और उक्त पत्रकार के साझा अभियान का परिणाम यह हुआ कि केंद्र पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। कुछ ही दिनों में संस्था और एमडी की जांच का काम सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। इन्हीं दिनों श्रीमती आयंगर के अनुसार एक बार ईश्वरदास से मिलने गयीं, तो उन्होंने कहा, "मैडम वक्त बदल चुका है। अर्जुन सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं हैं।" श्रीमती आयंगर इस बीच अनेक बार मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा व उच्चाधिकारियों से मिलीं। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने उनकी शिकायतों पर मौन साधे रखा और उच्चाधिकारियों ने डा० ईश्वरदास का हवाला देकर हाथ खींच लिया।

डा० ईश्वर दास

यूनियन कार्बाइड और सीआईए विभिन्न संगठनों के जरिये गैस पीड़ितों में सक्रिय हो रहे हैं जिससे उनका आक्रोश सरकार की ओर मोड़ा जा सके।

कदम आगे नहीं बढ़ सके : वोरा और मदर टेरेसा के साथ इंदिरा आयंगर (बीच में)

२३ वर्षीय केदार चौहान, ३२ वर्षीय केदार महतो और १६ वर्षीय मुहम्मद शकील उन लोगों में हैं जो रिजवान बाग स्थित प्रशिक्षण केंद्र में टाइपिंग, ब्रेल लिपि आदि सीख रहे थे। अंधत्व के शिकार इन तीनों लोगों के पास आजीविका का आज भी कोई साधन नहीं है तथा ये चाहते हैं कि काश वे अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते। केंद्र में प्रशिक्षण पाने वाले कमजोर तबके की लगभग तीन सौ गैस पीड़ित औरतों बच्चों और विकलांगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। विदेशी सहायता से वंचित होने के बाद भी केंद्र कुछ दिन और चलता, अगर आला अफसरों के इशारे पर नगर निगम के कर्मचारी जा कर शेड और आस-पास का निर्माण तोड़ न डालते। शेडों के विध्वंश, अधिकारियों की प्रताड़ना और सीबीआई की जांच के परिणामस्वरूप अंततोगत्वा ३१ मार्च, १९८७ को श्रीमती आयंगर को केंद्र बंद कर देना पड़ा। केंद्र के बंद होने से एक स्वयंसेवी संस्था के दीन-दुखियों के उत्थान के महत्वाकांक्षी सपने ने शैशंव में ही दम तोड़ दिया। कथित विदेशी सहायता और संदिग्ध चरित्र की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के बाद अगर केंद्र को बंद किया जाता, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। जांच के बाद दोषी पाये जाने की स्थिति में श्रीमती आयंगर समेत केंद्र के संचालकों को दंडित किया जाना भी युक्तिसंगत होता। मगर सिर्फ अपनी सनक और गैरसरकारी भाषाओं को पनपने न देने की सरकारी अफसरों की कुटिलता के कारण किसी नेकनीयत मिशन में रोड़े अटकाना और उसें ध्वस्त करना कहां तक उचित ठहराया जा सकता है। श्रीमती आयंगर जांच में निर्दोष पायी गयी हैं, यह महत्वपूर्ण है, मगर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र को अकाल मौत का फरमान सुनाने वाले शासन ने उन तीन सौ गरीब लोगों को प्रशिक्षण देकर अपने पावों पर खड़ा करने के लिए क्या जतन किया है जो आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं?

—सुधीर सक्सेना

क्या न्याय मिलेगा ? : सुगना

सुगना और केसर

माथुर के राज में औरत

सुगना और केसर प्रतीक हैं समाज के उस वर्ग की महिलाओं की, जिन्हें शक्तिशाली तबका मात्र जिंस समझता है और जब वे पुलिस के पास रक्षा के लिए जाती हैं, तो पुलिस भी उनके साथ वही पाशविक व्यवहार दोहराती है। सुगना के साथ यही हादसा हुआ है। पर केसर की व्यथा तो और भी मर्मभेदी है। बलात्कार की शिकार दो महिलाओं की व्यथा-कथा :

बेबस : सुगना के पिता नाथू (बायें) और मां झमकू

जयपुर से १६० किलोमीटर दूर टोंक जिले में लगभग एक हजार आबादी वाला छोटा-सा गांव है पनवाड़। इस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घर एक हिस्से में बने हैं, तो सवर्णों के घर अलग घेरे में नजर आते हैं। राजस्थान में इस तरह की बसावट आम है। वक्त के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को जोतने वाली जमीन का हक और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिला है। पर यह लाभ केवल पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित है। प्रदेश के ३६ हजार गांवों में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को 'वस्तु' की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

पनवाड़ गांव की सत्तरह वर्षीया सुगना बैरवा (चमार) जाति की है। हाल में उसके हाथ पीले हुए हैं। घर में एक बीस वर्षीय बड़ा भाई मोहन है। भूख और कुपोषण से जल्द ही बूढ़े हुए मां-बाप हैं। पांच बीघा जमीन को जोतने से पेट नहीं पलता, इसलिए संपन्न किसानों के खेतों में काम करने जाते हैं। गरीब के घर में पैदा होने वाली हर चीज बेजुबान समझी जाती है। इसी समझ से जवान हुए ठाकुर भरत सिंह और उसके साथी महावीर व जगदीश ने १७ फरवरी को चाकू की नोक पर सुगना की इज्जत लूट ली।

सुगना उस दिन चार बजे अपने पिता के खेत में कटी हुई फसल की जड़ें निकाल रही थी। बूढ़ा बाप और मां रोजी के लिए किसी अन्य खेत में काम कर रहे थे। बड़ा भाई मोहन घर पर था। तभी बबूल के पेड़ों से घिरे खेत में भरत सिंह और उसके अपराधी साथी चुपके से आये। भरत सिंह ने सुगना का मुंह बंद किया और पेड़ों के झुरमुट में उठा ले गये। पहले भरत सिंह ने सुगना की इज्जत लूटी और फिर बाकी दोनों साथियों को कुकृत्य करने का आदेश दिया। फिर खेतों-ही-खेतों में चाकू की नोक पर चलाते पनवाड़ गांव से पांच किलोमीटर दूर देवली कस्बे में ले गये। इस कस्बे में पूरी रात असहाय सुगना को तीनों की हवस का शिकार होना पड़ा।

फिर बलात्कार : अगले दिन सुगना देवली से चल कर अपने गांव पहुंची। परेशान घर वालों को जब सारा किस्सा सुनाया, तो बड़ा भाई मोहन अगले दिन पनवाड़ गांव की पुलिस चौकी पर सुगना के साथ रिपोर्ट लिखवाने गया। चौकी पर मौजूद हैड कांस्टेबिल खेमचंद चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, पर अगले दिन बीस फरवरी को शाम यह कह कर थाने ले गया कि बड़े साहब सुगना के बयान लेंगे। सुगना के साथ उसका बड़ा भाई मोहन भी चौकी पर गया। हैड कांस्टेबिल खेमचंद ने मोहन को चौकी के बाहर बैठने को कहा और सुगना को अन्दर ले जाकर अपराधी भरत सिंह की तरह मुंह बंद कर अपनी हवस मिटायी।

सुगना ने सारी कथा अपने भाई से कही, तो अगले दिन वह अपने पिता के साथ जिला हैड क्वार्टर टोंक पहुंचा। यहां पुलिस अधीक्षक अनिल खन्ना को सारा किस्सा सुनाया, तो वह तुरन्त उन्हें लेकर पनवाड़ गांव गये। सिपाही खेमचंद को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा तीन अन्य बलात्कारियों को भी हिरासत में ले लिया गया है।

लुटी हुई सुगना की व्यथा-कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। वह मां-बाप के साथ खेतों में काम करने जाती है, तो वहां लोग उससे हमदर्दी के बजाय ताने कसते हैं। ठाकुर जाति के कुछ लोग धमकी देते हैं कि उसने थाना-कचहरी में फरियाद करने की जुर्रत की, तो वे उसके हाथ-पांव तोड़ देंगे। यह सब तब हो रहा है, जब इस सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस-इ के टिकट पर लोकसभा के लिए सुगना की जाति के बनवारीलाल बैरवा दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। बनवारीलाल बैरवा १९७२ में राजस्थान विधानसभा के लिए चुने जाने पर हरिदेव जोशी मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री रहे हैं।

यह संवाददाता जब सुगना को तलाश करता पनवाड़ गांव पहुंचा, तो गांव में कोई यह बताने को तैयार नहीं था कि सुगना का मकान कौन सा है। बहरहाल, एक बच्चे ने घर बताया, तो उस पर ताला लगा था। उस अबोध बालक ने ही सुगना के पिता का खेत बताया। वहां सुगना के पिता नाथू अपने घुटनों में सिर दिये बेबस-से बैठे थे। जब उनसे सुगना के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी बोली में

साक्षात्कार/नाथू सिंह

आज भी सामंतों का आतंक है

टोंक जिले के 'टोडारायसिंह' निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक नाथूसिंह का 'पनवाड़' से सीधा संबंध है। पनवाड़ ग्राम इन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। सारे मसले पर नाथूसिंह की खामोशी आश्चर्यजनक थी। बजट सत्र के दौरान इन पंक्तियों के लिखे जाने तक विधायक ने अपनी जुबान विधानसभा में नहीं खोली थी। वैसे पनवाड़ गांव में पक्ष-विपक्ष का कोई भी जननेता 'माया' के पहुंचने तक नहीं पहुंचा था। प्रस्तुत हैं, विधायक से बातचीत के कुछ अंश :

माया : पनवाड़ ग्राम में सुगना बैरवा के साथ बलात्कार हुआ, अपने निर्वाचन क्षेत्र की इस घटना पर आप मौन क्यों हैं?

सिंह : नहीं, मौन नहीं हूं। जैसे ही मुझे घटना का पता लगा, मैंने पुलिस अधीक्षक अनिल खन्ना से कार्यवाही करने के लिए कहा। नतीजा यह हुआ कि सारे अपराधी पकड़े गये हैं। अपने दल के लोगों को भी मैंने कहा है कि सारी घटना का विस्तार से पता लगायें। मैं स्वयं भी वहां जाऊंगा। वैसे पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर ली है, फिर भी जरूरी हुआ, तो मसला विधानसभा में उठाऊंगा।

माया : पुलिस अधीक्षक की तत्परता से अपराधी पकड़े तो गये हैं, लेकिन गवाहियों के अभाव में क्या उन्हें दंड मिल सकेगा?

सिंह : देखिए, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा। दबने-डरने और घबराने से काम नहीं चलेगा। हम ऐसी ही जन-चेतना लोगों में पैदा कर रहे हैं।

माया : सुगना के साथ घटी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे?

सिंह : इसके लिए पूरे जिले में एक मुहिम चलानी होगी। टोंक जिला बहुत पिछड़ा जिला है। वहां, आज भी समाज के कमजोर तबकों पर यदाकदा अत्याचार हो जाते हैं। मैं साल में पांच बार अपने क्षेत्र का दौरा करता हूं। इन दौरों के दौरान मैं लोगों को उनके हकों के लिए हौसला देता हूं। लोगों को भयमुक्त करना मेरा ध्येय होता है। किसी भी अत्याचार की सूचना मुझ तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, इसके लिए लोगों को तैयार करता हूं। अब पिछड़ी जाति के लोग, नीचे तबके के लोग अन्याय बरदाश्त नहीं करते। सुगना को ही आपने देखा। न्याय के लिए उसने हर दरवाजा खटखटाया है।

माया : पर, सामंती मनोवृत्ति तो अपना खेल आज भी खेल रही है।

सिंह : इस मनोवृत्ति से मेरा परिचय नया है। जयपुर जिले में जब मेरा निर्वाचन क्षेत्र था, मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ेपन के कारण कुछ असरदार लोगों को आजाद भारत का अहसास नहीं है। ये लोग बड़ी तरकीब से सत्ता के साथ रहते हैं और सरकार के सहयोग से जुल्म करते हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को खड़ा कर रहे हैं।

माया : सुना है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में आज भी सामंतशाही चलती है?

सिंह : हां, सच है। आज भी सामंतों का आतंक है। सरकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ आम जनता से छीन कर वे अपने हिस्से में ले जाते हैं। पंचायतों के चुनावों की ठेकेदारी, अकाल, राहत·बांटने की ठेकेदारी, सब पर ये अपना कब्जा आंख दिखा कर हासिल करने के आदी रहे हैं। मैं जब इस निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा हुआ, तो 'मेहरु' गांव में मुझे ठाकुरशाही का नजारा देखने को मिला। ठाकुर साहब ने धौंस दी कि मैं वहां मीटिंग नहीं कर सकता। ठाकुर साहब को सरपंची अलग हासिल थी। खैर, मैंने जनता के सहयोग से मीटिंग भी की और जीता भी। पर, आम लोगों का यही कहना था कि आपकी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में गढ़ में ले जाकर जूते मारे जायेंगे। मैं ही जानता हूं कि कितनी मुश्किल से मैंने लोगों को भयमुक्त किया है।

माया : आपने राज्य के गृह विभाग को इस संबंध में क्या आगाह किया है?

सिंह : मैंने जिले की सतर्कता समिति में ऐसे मामले उठाये हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहले प्रशासन, जहां इन असरदार लोगों के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था, अब गरीब की मदद के लिए बाध्य है।

—ओ॰सै॰

बताया, "सुगना और उसकी मां किसी खेत पर काम करने गयी हैं। 'माया' ने जानना चाहा कि यह सब कैसे हुआ? उनका कहना था—"उसी से पूछ लीजिए।"

जिस खेत पर सुगना और उसकी मां झमकू काम कर रही थीं, नाथू हमें वहां ले गये। सहमी हुई सुगना को जब इस संवाददाता ने विश्वास दिलाया कि हम उसकी मदद के लिए आये हैं, तो उसने आप बीती सुनायी। मासूम सुगना का कहना था कि भरत सिंह की जात वाले उसे धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं, "अभी हुआ क्या है, अब होगा तेरे साथ, हाथ-पांव तोड़ देंगे तेरे।" सुगना की नस-नस में डर समाया था। उसे अपनी जात वाली पड़ोसी औरतों पर गुस्सा था जो उसकी बेबसी पर ताने कसती हैं। सुगना की मां झमकू कहती है, "हम गांव छोड़ कर कहां जायें?" पिता नाथू गुमसुम बना रहता है। भाई लोग अपनी लूटी हुई इज्जत को बेबसी से बर्दास्त कर रहे हैं।

इसी तरह की एक घटना अलवर जिले के टपूकड़ा कस्बे में नाबालिग हरिजन लड़की केसर के साथ घटी है। केसर टपूकड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की छठी कक्षा की छात्रा है। कस्बे में शराब का व्यवसाय करने वाले दो लोगों और एक राजनेता पर आरोप है कि उन्होंने केसर के साथ बलात्कार किया। एक फरवरी को घटी इस घटना को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में उठा कर लोकदल-ब के विधायक जगपाल सिंह यादव ने सनसनी फैला दी। उनका आरोप था कि अलवर के जिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के॰के॰ सिंह को घटना की जांच का काम सौंपा गया है, उसने अभियुक्तों को दस दिन थाने में बंद रखने के बाद ८५ हजार रुपए लेकर रिहा कर दिया। यादव ने सदन में यह भी बताया कि के॰के॰ सिंह पंद्रह हजार रुपए देकर कुमारी केसर के मां-बाप को बयान बदलने के लिए बाध्य कर रहा है। मजबूरन इन लोगों ने पिछले दिनों टपूकड़ा गांव छोड़ दिया।

इसके विपरीत गृह राज्यमंत्री लक्ष्मण सिंह का जवाब था कि अलवर के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ सौ लोगों ने उसके पास लिखित शिकायत की है कि कुमारी केसर के आरोप झूठे हैं, कुमारी केसर की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल रेकार्ड में उसकी उम्र ग्यारह वर्ष दर्ज है, जबकि मेडिकल जांच से वह सत्तरह साल की साबित होती है। बहरहाल लक्ष्मण सिंह के साथ-साथ मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने सदन में घोषणा की कि अभियुक्तों को बख्शा नहीं जायेगा और जांच सीआईडी से करवाई जायेगी।

चूंकि यह मामला विधानसभा में पहुंच गया, इसलिए न्याय मिलने की संभावना है, अन्यथा सुगना की तरह केसर के पास भी अत्याचार बरदाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं होता।

—ओम सैनी

छाया : गोपाल [illegible]

हरकिशन लाल भगत

दिल्ली का सुल्तान

बा अदब, बा मुलाहिजा....दिल्ली के बेताज बादशाह हरशिन लाल भगत

यों तो हरकिशन लाल भगत ६८ वर्ष के हैं, उनकी ठोडी दोहरी हो चुकी है और गाल शिथिल, लेकिन उनके सिर पर बचे हुए बालों के चमकते कालेपन से ऐसा नहीं लगता कि भगत बुढ़ा गये हैं। उम्र की बात छोड़ भी दें, तो भी भगत का दिल्ली में राजनीतिक यौवन अपने पूरे निखार पर है। अर्जुन सिंह के चले जाने और टाइटलर के नीचे आ जाने से भगत का सितारा और भी बुलंद हो गया है। भगत ऐसे कौन से गुर जानते हैं कि उनको इस समय दिल्ली की राजनीति का बेताज बादशाह माना जाता है ?

दिल्ली में स्थानीय निकायों के चुनावों के टाले जाने की घटना ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति पर पूरे देश का ध्यान केंद्रित कर दिया है। पिछले पांच सालों से दिल्ली की राजनीति में दिल्ली के लौह पुरुष एच०के०एल० भगत (संसदीय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री) अपनी पार्टी के अंदर और बाहर के सभी विरोधों व राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए बेताज बादशाह की भांति अपना दबदबा बनाये हुए हैं। अपने समर्थकों के बीच जहां वह 'किंग-मेकर' माने जाते हैं, वहीं उनके विरोधी भी उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कायल हैं। भारतीय जनता पार्टी और स्वयं इंका के भगत विरोधी नेता इस बात को जनता के सामने कहने से नहीं हिचकते कि ये चुनाव कांग्रेस-इ को भाजपा के हाथों संभावित करारी हार को बचाने के उद्देश्य से टाले गये हैं। अनाधिकृत तौर पर वे इसे अपने खिलाफ चल रही आलोचनाओं की लहर को समाप्त करने के लिए भगत का गूढ़ षड्यंत्र भी मानते हैं। उनका कहना है कि भगत अपने पत्तों को सीने से चिपकाए हुए हैं और अंदेशा है कि वह शायद दिल्ली में विधान सभा की स्थापना या अन्य कोई करिश्मा करके कांग्रेस-इ को अभूतपूर्व बहुमत दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश के हृदयस्थल की राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। वे याद करते हैं कि किस प्रकार भगत ने १९८३ में दिल्ली के स्थानीय निकायों के चुनावों में विजय प्राप्त की थी और किस तरह अकेले दम पर उन्होंने १९८४ में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस-इ को विजयी बनाया था।

भगत का उदय: दिल्ली की राजनीति में भगत का उदय एक अभूतपूर्व घटना मानी जा सकती है। वह जगदीश टाइटलर के संरक्षक संजय गांधी की २३ जून, १९८० को हुई मृत्यु के पश्चात ही प्रकाश में आने शुरू हुए। भगत ने धीरे-धीरे राजीव गांधी की समीपता हासिल की और अरुण नेहरू के खास चहेते साबित हुए। १९८३ में भगत ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से अरुण नेहरू के साथ मिलकर स्थानीय निकायों के चुनावों में टिकट बांटने का कार्य किया था। उन्होंने बड़ी सफाई से अपने विरोधियों—जगदीश टाइटलर, ललित माकन और भीकू राम जैन (सांसद) के समर्थकों का पत्ता साफ कर दिया। भगत ने जिन वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया, उनमें अमरनाथ चावला, श्रीमती सविता बहन, मांगेराम, किशन स्वरूप, शिवचरन गुप्ता, अनवर देहलवी और चौधरी दलीप सिंह प्रमुख थे।

महानगर परिषद के एक सदस्य राधेश्याम खन्ना को भगत ने सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया था, क्योंकि उनके संबंध भीकूराम जैन से थे। उनके अनुसार, "भगत ने टिकट उन्हीं लोगों को दिये, जिनका कोई जनाधार नहीं था और जिनकी एकमात्र योग्यता भगत के प्रति वफादारी थी। भला हो भगत का, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का एक 'मीटर रीडर' और राशन की दुकान चलानेवाला एक व्यक्ति टिकट पा गया। एक व्यक्ति जो पहले नगर निगम का एक कर्मचारी था, वह चुनाव जीतकर निगम के एक विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष बन गया। श्री खन्ना का तो यहां तक दावा है कि भगत का एक प्रत्याशी तो अपने हस्ताक्षर तक करना नहीं जानता था और ऐसे लोग तो अनेक थे, जो दर्जा आठ तक भी नहीं पढ़े थे। दिल्ली के स्थानीय निकायों के लिए टिकट प्राप्त करनेवाला एक व्यक्ति और कोई नहीं खुद भगत का ड्राइवर था।

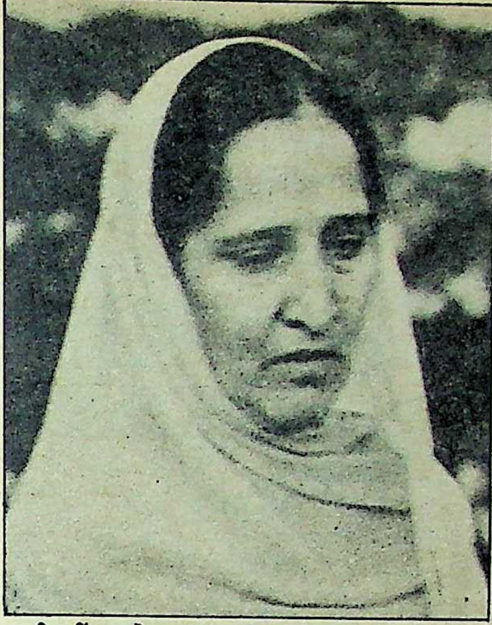

दलीप सिंह को मात: ताजदार बाबर

बहरहाल, भगत के उम्मीदवार योग्य थे अथवा अयोग्य, वे भाजपा से सत्ता हथियाने में सफल रहे और उन्होंने दिल्ली पर भगत की पकड़ को और मजबूत कर दिया। जो भी हो, १० मई, १९८३ को राजीव गांधी के सीधे हस्तक्षेप के कारण भगत ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और चौधरी दलीप सिंह के लिए रास्ता साफ कर दिया। चौधरी साहब का अध्यक्ष बनाया जाना, जगदीश टाइटलर और भीकूराम जैन की संयुक्त विजय के रूप में देखा गया। लेकिन इससे भगत के प्रभामंडल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लगभग सारा प्रशासन भगत गुट के नियंत्रण में पहुंच चुका था और ललित माकन जो जनवरी १९८३ में कांग्रेस में शामिल हुए थे अपना पैर जमाने की कोशिश में लगे थे।

चौधरी दलीप सिंह के लिए अध्यक्ष का कार्य सरल नहीं था, क्योंकि वह भगत के आदमी नहीं थे। 'माया' के साथ हुई बातचीत में उन्होंने बताया, "पहले ही दिन एम०एल० फोतेदार ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया, मेरे वहां पहुंचने पर उन्होंने अरुण नेहरू को फोन मिलाया और व्यंग्य पूर्वक बोले, "आपके दोस्त आये हैं।" जब अरुण नेहरू आये, उनके हाथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रस्तावित पदाधिकारियों की एक सूची थी। मुझसे उस सूची पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। मैंने बिना श्रीमती इंदिरा गांधी से बात किये हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बाद में मामला सुलझ गया, पर अरुण नेहरू हमेशा के लिए मेरे पीछे पड़ गये।" भगत के साथ अपने संबंधों के बारे में दलीप सिंह का कहना है, "भगतजी मुझसे इसलिए नाराज थे कि मैंने एक पद के लिए ऐसे प्रत्याशी का चयन किया था जो कि उनकी निगाह में उक्त पद के काबिल न था।" जो भी हो दलीप सिंह को इस स्थिति से राजीव गांधी ने उबार लिया, क्योंकि वह भगत के अधिकतर व्यक्तियों को पद देने के लिए सहमत हो गये थे। केवल दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद भगत-विरोधी सूरत सिंह चौधरी को दिया गया। अन्य सभी समितियों पर भगत के आदमियों का कब्जा बना रहा। मेयर मोहिंदर सिंह साथी और मेयर जे०पी० अग्रवाल (जिनके पिता आर०सी० अग्रवाल जो कभी दिल्ली के डिप्टी मेयर रह चुके हैं), को भी भगत का आदमी माना गया। एक साल के अंदर ही भगत ने बड़ी चतुराई से सूरत सिंह को बाहर निकालकर उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने आदमी जे०पी० अग्रवाल की नियुक्ति कर दी, जिन पर चौधरी सूरत सिंह काबिज थे। जे०पी० अग्रवाल इसके पूर्व उपमेयर थे, अब यह पद भगत के एक अन्य आदमी दीपचंद बंधु को दे दिया गया। बहरहाल, चौधरी दलीप सिंह ने फिर से अपने अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश की और भगत द्वारा नामांकित लोगों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते भाजपा की पूर्णिमा सेठी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने से रिक्त हुई दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान समिति के सदस्य के स्थान को भरने के लिए हरचरण सिंह जोश को अपना नामांकन भरने का निर्देश जारी कर दिया। दलीप सिंह ने मुश्ताक राय खन्ना को भी निगम की शक्तिशाली स्थायी समिति का सदस्य नामांकित कर दिया। लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल ने भगत के इशारे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशों को रद्दी की टोकरी में फेंककर राय सिंह और आमोद कुमार को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के तथा के०एस० गुजराल को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित कर दिया।

विरोधियों को शिकस्त: ९ अप्रैल, १९८४ को दलीप सिंह ने जयप्रकाश अग्रवाल को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के निर्देशों की अवमानना करने के विरुद्ध कठोर पत्र लिखकर आदेश दिया कि वह तत्काल अपने द्वारा नामांकित प्रत्याशियों को हटा लें। लेकिन अग्रवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह भगत की कूटनीति का ही कमाल था कि दलीप सिंह को ही अपने लिखित आदेशों को वापस लेना पड़ा और जोश भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए विवश हो गये। जोश ने बताया, "मैंने बाद में दलीप सिंह से कहा था कि इस तरह झुक जाना अपमानजनक है।"

अगले मास ही दलीप सिंह को प्रति प्रहार करने का अवसर मिल गया। भगत के एक आदमी पार्षद हरबीर सिंह हरनोटिया पर दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टुडेंट्स होस्टल में सीलमपुर की एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा और हरनोटिया को उनके चार

साथियों सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दलीप सिंह ने बड़ी तेजी से कार्यवाही कर २५ मई, १९८४ को हरनोंटिया को कांग्रेस-इ की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। भगत गुट दलीप सिंह की इस कार्यवाही से कुपित जरूर हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सका, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस-इ के अखिल भारतीय महासचिव राजीव गांधी का दलीप सिंह को वरदहस्त प्राप्त था। अतः भगत गुट ने अपना पैंतरा बदलकर दलीप सिंह के बजाय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के महासचिव जगदीश टाइटलर को अपना निशाना बनाने की रणनीति बना ली। अफवाह अभियान चलाया गया कि जगदीश टाइटलर संजय मंच की प्रमुख मेनका गांधी से गुपचुप सांठगांठ में लिप्त हैं। अगस्त के शुरुआती दिनों में भगत गुट के दो पार्षदों—चंदर अमृत और जगदीश आनंद ने सार्वजनिक रूप से टाइटलर पर आवासों के आवंटन में किंग्जवे कैंप इलाके के शरणार्थियों के साथ पक्षपात कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। एक सप्ताह बाद ही टाइटलर ने इसके जवाब में भगत गुट के दो वरिष्ठ नेताओं पर उक्त दोनों स्थानीय नेताओं को ऐसा आरोप लगाने की शह देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। १४ अगस्त, १९८४ को टाइटलर के कहने पर दलीप सिंह ने इन दोनों नेताओं—चंदर अमृत और जगदीश आनंद को टाइटलर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दूसरी ओर, भगत गुट ने हाई कमांड के कान भरे कि दलीप सिंह टाइटलर की रहनुमाई में एकजुट हो रहे मेनका गांधी-समर्थकों के गुट को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरे ही दिन अर्थात १५ अगस्त, १९८४ को दलीप सिंह को ही अपने पद से इस्तीफा दे देने का इशारा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दलीप सिंह ने 'माया' को बताया, "मैं बीमार था और बिस्तरे पर पड़ा था। शिवशंकर मेरे घर आये और मुझसे कहा कि आप बीमार रहते हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी का काम ठीक तरह नहीं होता, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। बहरहाल, मैंने इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं कांग्रेस-इ महासचिव से बात नहीं कर लूंगा, तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा।"

बहरहाल, अ०भा० कांग्रेस-इ कमेटी ने दलीप सिंह के त्यागपत्र की प्रतीक्षा नहीं की और उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष पद से बेतकल्लुफी से हटा दिया। १६ अगस्त, १९८४ को अभी वह दोपहर भोजन के बाद आराम कर ही रहे थे कि उन्हें तत्कालीन कांग्रेस-इ महासचिव श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने फोन पर बड़ी बेरुखी से सूचना दी कि उनके स्थान पर ताजदार बाबर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है।

अब दिल्ली में प्रशासन और पार्टी दोनों पर भगत गुट की पकड़ मजबूत हो गयी। इससे भगत-विरोधियों के पास बगावत करने के सिवा कोई चारा शेष नहीं रहा था। १७ सितंबर, १९८४ को भीखूराम जैन, चौधरी दलीप सिंह, चौधरी सूरत सिंह और भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद किशन स्वरूप सहित भगत विरोधी १०० कांग्रेसियों ने दिल्ली के विट्ठलभाई पटेल हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया। भोज के अवसर हुई बैठक में भगत के विरुद्ध माहौल बेहद सरगर्म था। भगत-गुट को पार्टी और प्रशासन में बेअसर करने की एक-से बढ़कर-एक रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ और अंततः एक प्रस्ताव के जरिए यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री और अ०भा० कांग्रेस-इ अध्यक्ष इंदिरा गांधी को भगत के तानाशाही रवैये और उनके द्वारा जमीन से जुड़े कांग्रेसियों को उपेक्षित करने के मामलों से अवगत कराया जाये। भगत-विरोध में आयोजित इस बैठक को सबसे बड़ा झटका स्वयं जगदीश टाइटलर व ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने दिया। इन दोनों नेताओं ने भोज में शामिल होने का वायदा किया था, लेकिन ऐन वक्त पर वे ठंडे पड़ गये और बैठक में शामिल नहीं हुए।

भगत के अंधभक्त: मोहिंदर सिंह साथी

बहरहाल, योजनानुसार उक्त प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी को दे दिया गया। श्रीमती गांधी ने भी हस्तक्षेप करने का मन बना लिया था। उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में २८ सितंबर, १९८४ को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन को श्रीमती गांधी के अतिरिक्त राजीव गांधी, अब्दुल गफूर, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, पी० शिवशंकर और ताजदार बाबर ने भी संबोधित किया। भगत गुट ने इस सम्मेलन की सारी व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि उनके विरोधी कुछ कर नहीं सके। अपने भाषण में श्रीमती गांधी ने कहा कि संकट के समय में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए—हर एक को संगठित हो जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेसियों से एकजुट होने का आह्वान किया। राजीव गांधी अमेठी से लौटने के तुरंत बाद हवाई अड्डे से सीधे सम्मेलन स्थल पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेसियों से संगठित होकर कार्य करने और आम जनता का [illegible] उन्हें कांग्रेस-इ पार्टी की उपलब्धियों से अवगत कराने का अनुरोध किया। विडंबना यह है कि जिन भगत के खिलाफ असंतुष्ट सक्रिय थे, उन्होंने ही सम्मेलन में पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अन्य सभी वक्ता भी भगत समर्थक थे। भीखूराम जैन, दलीप सिंह, शिवचरण गुप्ता, हीरा सिंह, दीपचंद शर्मा, फतह सिंह और अनवर अली देहलवी जैसे भगत-विरोधी नेताओं को बोलने का अवसर ही नहीं मिला।

बेताज बादशाह: इसके बाद श्रीमती गांधी हत्याकांड हुआ और आम चुनावों की घोषणा हो गयी। राजीव गांधी युवा लोगों को टिकट देने के पक्ष में थे। इसी कारण जगदीश टाइटलर को सदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिल गया, जबकि भगत एवं सदर क्षेत्र के सभी निगम पार्षदों और कार्यकारी पार्षदों ने टाइटलर को टिकट दिये जाने का विरोध किया था। इसी प्रकार भगत अपने आदमी सज्जन कुमार को बाहरी दिल्ली क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिलवाने में भी असफल रहे। दक्षिणी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का टिकट भी ललित माकन को मिल गया, जबकि इस सीट पर भगत चरणजीत सिंह को खड़ा करना चाहते थे। बहरहाल, युवा लोगों को टिकट देने के नाम पर भगत अपने प्रखर विरोधी और भूतपूर्व सांसद भीखूराम जैन का चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से पत्ता साफ करने में सफल हो गये। यहां से उन्होंने अपने खास आदमी जे०पी० अग्रवाल को टिकट दिलवा दिया, जबकि श्री अग्रवाल ने नगर निगम तक का चुनाव नहीं लड़ा था। इस प्रकार भगत ने टाइटलर गुट के एक प्रखर सदस्य भीखूराम जैन को कमजोर कर दिया, लेकिन ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन भगत के विरोध में टाइटलर के साथ हो गये। महानगर पार्षद अर्जुन दास भगत-समर्थक माने जाते थे, लेकिन वह भी टाइटलर के खेमे में चले गये। नयी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित के०सी० पंत इन दो खेमों की आपसी लड़ाई में तटस्थ बने रहे। जून १९८५ तक भगत-विरोधियों ने फिर से एकजुट होना शुरू कर दिया था। १९ जून, १९८५ को ललित माकन ने भगत पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली में पार्टी और स्थानीय निकायों में भ्रष्ट और अक्षम लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रखा है। उन्होंने भगत के ड्राइवर का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। उल्लेखनीय है कि भगत के ड्राइवर द्वारा पार्षद बनने के बाद खरीदी गयी दो कारों और अन्य संपत्ति पर लोगों की उंगलियां उठने लगी थीं। ललित माकन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के महासचिव प्रेम सरवरिया पर भी बरसे जो बिना किसी अधिकार के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के उपाध्यक्षों को पार्टी-बैठकों में शामिल न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे थे।

टाइटलर अब न केवल सांसद थे, बल्कि वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के महासचिव भी थे। ललित माकन द्वारा भगत पर प्रहार करने के तीन

दिनों बाद ही २२ जून, १९८५ को टाइटलर ने आरोप लगाया कि भगत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी को अपनी घरेलू संस्था की तरह चला रहे हैं। टाइटलर के समर्थकों का कहना था कि भगत ने पार्टी और दिल्लीवासियों की सबसे बड़ी 'कुसेवा' यही की है कि उन्होंने पार्टी और सरकार में अक्षम और भ्रष्ट लोगों को तैनात किया। भगत विरोधी गुट में अब सांसद विश्वबंधु गुप्ता व सुंदरवती नवल प्रभाकर, महानगर पार्षद रामलाल, भूतपूर्व सांसद ए०एन० चावला, भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद मांधेराम तथा नगर निगम पार्षद दीपचंद शर्मा व हरचरण सिंह जोश भी शामिल हो गये थे। लेकिन भगत का सितारा बुलंद था। आतंकवादियों ने ललित माकन और अर्जुन दास को रास्ते से हटा दिया। इस प्रकार चौधरी सूरत सिंह, चौधरी दलीप सिंह और भीखू राम जैन के सत्ता से बाहर हो जाने और ललित माकन तथा अर्जुन दास के दिल्ली के राजनीतिक मंच से हट जाने के कारण भगत दिल्ली के बेताज बादशाह बन गये।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी में ताजदार बाबर, प्रशासन में मुख्य कार्यकारी पार्षद के रूप में जग प्रवेश चंद्र, नगर निगम के मेयर के रूप में मोहिंदर सिंह साथी तथा सभी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के रूप में भगत के आदमियों के स्थापित हो जाने के कारण टाइटलर गुट बेअसर हो गया। दूसरी ओर मंत्री-पद के लिए टाइटलर द्वारा भगत, अरुण नेहरू व फोतेदार से समझौता कर लिये जाने के कारण इनके रहे-सहे हौसले भी पस्त हो गये और हरचरण सिंह जोश, सूरत सिंह, जगदीश आनंद और राधेश्याम खन्ना जैसों के छोटे मगर मुखर भगत-विरोधी गुट का कोई रहबर नहीं रहा।

बेअसर अर्जुन सिंह : ललित माकन की हत्या के कारण रिक्त हुई दक्षिणी संसदीय सीट से अर्जुन सिंह ने उपचुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने भगत-विरोधियों का थोड़ा-बहुत मुकाबला जरूर किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में भगत के वर्चस्व को कभी चुनौती नहीं दी। बहरहाल, उन्हें अंजना कंवर को दिल्ली का उपमेयर नियुक्त करवाने में थोड़ी सफलता जरूर मिली। यहां तक कि पार्षद और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य दीपचंद शर्मा तो बीच रास्ते में ही पाला बदलकर भगत के खेमे में चले गये। श्री शर्मा को तत्काल इसके लिए पुरस्कृत कर नगर निगम की शक्तिशाली स्थायी समिति का अध्यक्ष बना दिया। अर्जुन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह बाहरी आदमी थे और दिल्ली के कांग्रेसियों पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो सकी। दिल्ली कांग्रेस-इ के खेमे में ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में हुए शराब घोटाले काण्ड पर मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय का फैसला आने के बाद अर्जुन सिंह ने भगत के वर्चस्व के विरुद्ध अपना संघर्ष छोड़ दिया। शराब घोटाला कांड के समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

भगत का रुतबा : दिल्ली में भगत की अब 'किंग-मेकर' की छवि बन चुकी थी। उनके रुतबे का

भगत से समझौता : जगदीश टाइटलर

आलम यह था कि दिल्ली के कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बजाय भगत की बातों को कहीं अधिक गंभीरता से लेते थे। ऐसे अनेक अवसर आये, जब कांग्रेस-इ अध्यक्ष राजीव गांधी का वरदहस्त होने के बावजूद भगत-विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। भगत-विरोधी पार्षद हरचरण सिंह जोश एक घटना का हवाला देते हैं, जो संभवतः १ अप्रैल, १९८७ को घटित हुई थी।

भगत ने तदर्थ नियुक्ति समिति के लिए दीपचंद बंधु और कार्य समिति के अध्यक्ष पद के लिए मंगतराम सिंघल का नाम प्रस्तावित किया था। जोश दावा करते हैं कि वह १ अप्रैल को राजीव गांधी से मिले थे और उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि भगत द्वारा प्रस्तावित उक्त दोनों प्रत्याशी उक्त पदों के काबिल नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों से ग्रस्त हैं। राजीव गांधी उनसे सहमत थे कि ऐसे लोगों को पार्टी के हित में उक्त पदों पर नामांकित न किया जाये। उन्होंने जोश के सुझाव पर भगत-विरोधियों महेंद्र कुमार जैन और जगदीश आनंद के नामों की क्रमशः तदर्थ नियुक्ति समिति तथा कार्य समिति के अध्यक्ष-पद के लिए संस्तुति कर दी। इतना ही नहीं अपने इस फैसले से राजीव गांधी ने के०एम० पन्निकर को भी तत्काल अवगत कर दिया और संसद भवन चले गये, जहां से उन्हें करनाल तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए करनाल रवाना होना था। जोश भगत के विरुद्ध विजय-दुदंभी बजाते हुए लौटे और उन्होंने भगत-समर्थक मेयर मोहिंदर सिंह साथी से राजीव गांधी द्वारा स्वीकृत लोगों का उक्त पदों के लिए नामांकन भरने को कहा। पन्निकर ने भी साथी को राजीव गांधी के फैसले की जानकारी दी, लेकिन साथी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नामांकन पत्र भरे जाने का वह अंतिम दिन था और तब तक दोपहर हो चुकी थी जबकि उस दिन शाम पांच बजे तक हर सूरत में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर देना जरूरी था। लेकिन जोश अपने इस अभियान में कामयाब नहीं हो सके। हुआ यह कि उस दिन भगत खुद राजीव गांधी के साथ करनाल गये थे, जहां वह राजीव गांधी को यह समझाने में सफल हो गये कि जोश विश्वसनीय व्यक्ति नहीं हैं। अतः आज सुबह लिये गये फैसले को रद्द कर देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अंतिम क्षणों में महेंद्र सिंह साथी के नाम करनाल से फोन आया कि भगत के प्रत्याशियों के ही नामांकन पत्र भरे जायें।

भगत की दिक्कतें : यद्यपि भगत १९८३ से दिल्ली के बेताज बादशाह बने हुए हैं, लेकिन १९८५ के बाद से उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर उन पर अधिकाधिक छींटाकशी शुरू हो गयी है। गृह मंत्रालय ने यद्यपि इस बात का खंडन कर दिया है, लेकिन यह अफवाह दिल्ली में जोरों से फैली थी कि आयकरवालों ने भगत के घर व अन्य ठिकानों पर छापा मारा था। १९८४ में दिल्ली में हुए सिख-विरोधी दंगों में उनकी भूमिका को लेकर बाद में उनकी काफी आलोचना हुई। जन स्वातंत्र्य संगठन (सिविल लिबर्टीज आर्गनाइजेशन) ने भगत की खुली आलोचना की, तो रंगनाथ मिश्र आयोग की संस्तुति से गठित जैन-बनर्जी समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने भगत के चहेते सज्जन कुमार के खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया, जबकि भगत सज्जन कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी का अध्यक्ष बनवाने की तिकड़म में लगे थे। भगत को भय था कि उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। अतः जैन-बनर्जी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रकरण कायम करने के खिलाफ दिल्ली उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जहां भगत-समर्थकों की विजय हुई और उच्चन्यायालय ने जैन-बनर्जी समिति की सिफारिशों पर प्रकरण-कायम करने के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर दी। इस जीत के बावजूद भगत के अनेक कट्टर समर्थक उनके विरोधी खेमे में चले गये हैं। जयप्रकाश अग्रवाल को भगत ने आगे बढ़ाया था, लेकिन वह खेमा बदलकर टाइटलर के साथ हो गये। भगत के लिए सर्वाधिक कष्टकर प्रसंग तो तब उपस्थित हुआ, जब दिल्ली के मामलों में कांग्रेस-इ के अखिल भारतीय महासचिव आस्कर फर्नांडीज को सर्वेसर्वा बना दिया गया। उन्होंने ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नामांकित करना शुरू कर दिया जो भगत-विरोधी के रूप में एक लंबे अरसे से विख्यात थे। उदाहरण के तौर पर हरचरण सिंह जोश को उन्होंने स्थायी समिति और जगदीश आनंद को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान समिति का सदस्य नामांकित कर दिया। पिछले तीन सालों से वे दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक बने हुए थे। बहरहाल, भगत के वर्चस्व को उखाड़ फेंकना सरल नहीं है। उक्त नियुक्तियों से उन्हें किंचित झटका जरूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह उनके प्रभाव के अंत की शुरुआत है, क्योंकि पार्टी और प्रशासन के बाकी सभी पदों पर भगत के आदमी फिर छा गये हैं और दिल्ली की राजनीति में भगत की मजबूत पकड़ बरकरार है।

—अभय अग्रवाल

अफसर बनाम विधायक

एक दूसरे की पिटाई की नौबत

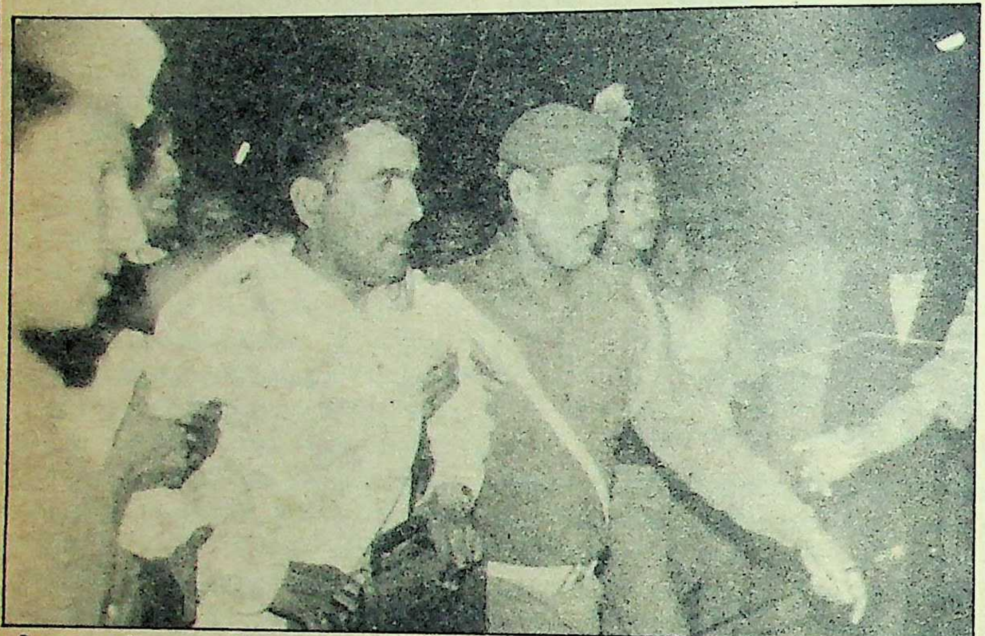

पुलिस द्वारा बीच-बचाव : विधायक और सुरक्षाकर्मी

परीक्षा केंद्र बदलने जैसे मामूली मसले को लेकर सचिवालय के कर्मचारियों और विधायकों के बीच हिंसक हाथापाई क्यों हुई ? कार्यपालिका और विधायिका के बीच बढ़ता तनाव क्या मोड़ लेगा ?

उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आई०ए०एस० अधिकारी और जनप्रतिनिधि ताल ठोंक कर आमने-सामने आ गये हैं। नौकरशाही और राजनीतिज्ञों का यह टकराव २ मार्च, १९८८ को उस समय शुरू हुआ, जब कुछ विपक्षी विधायकों ने प्रदेश के शिक्षा सचिव जगदीश चन्द्र पंत का घेराव कर उनके साथ अभद्रता की और जवाब में सचिवालय कर्मियों ने विधायकों की जमकर पिटाई की। आईएएस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस टकराहट ने कई गंभीर मुद्दों पर सवालिया चिह्न लगा दिया है। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के बीच नये संघर्ष की शुरुआत हो गयी है।

यदि यह कहा जाये कि उत्तर प्रदेश में अफ़सरशाही का ही राज्य है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का भी क्रियान्वयन नहीं होता है। अधिकारी इन आदेशों को अपनी इच्छा के अनुरूप घुमा देता है। आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई ?

कुछ वर्षों पूर्व तक मुख्यमंत्री का मात्र एक सचिव होता था, जो उनका सारा कार्य देखता था। उसे याद रहता था कि मुख्यमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या आदेश जारी किये हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के पास तीन सचिव, दो विशेष सचिव, तीन संयुक्त सचिव, दो उपसचिव के अतिरिक्त आधा दर्जन अन्य सचिव हैं। यही अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय की रीढ़ हैं। इन्हीं का कार्य मुख्यमंत्री के आदेशों को क्रियान्वित करना है।

हालत तो यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री इतने अधिक आदेश पारित करने लगे हैं कि उन्हें स्वयं याद नहीं रहता कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या आदेश जारी किया था। विधायकों की आम शिकायत है कि इसी कमजोरी का लाभ उठाकर नौकरशाह मुख्यमंत्री के आदेश को अपनी इच्छानुसार फाइलों पर घुमा देते हैं। इन अधिकारियों से आदेशों का सही अनुपालन करवाने के वास्ते विधायकों को जी-हुजूरी तक करनी पड़ती है। शिक्षा सचिव के साथ हुए व्यवहार के पीछे भी यही स्थिति थी।

कारण : झगड़े की शुरुआत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा का केंद्र बदलने को लेकर हुई। मेरठ के करनावल कस्बे में स्थित सर्वहितकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाईस्कूल का परीक्षाकेन्द्र १५ किलोमीटर दूर 'सरधना सेंट जोजफ स्कूल' रखा गया था। जबकि करनावल से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर 'शालिग्राम शर्मा स्मारक इंटर कालेज' है। ३० दिसम्बर, १९८७ को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह ने विधायक भोपाल सिह के ज्ञापन पर छात्राओं के परीक्षा केन्द्र बदलने के निर्देश शिक्षा सचिव जगदीश चन्द्र पंत को दिये थे। मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन २ मार्च १९८८ तक नहीं हो सका।

२ मार्च को दोपहर विधायक भोपाल सिह, वीरेंद्र सिह, किरण पाल सिह, कुशल पाल सिह, जवाहर सिह यादव सहित डेढ़ दर्जन विधायक विधान भवन स्थित शिक्षा सचिव के कार्यालय पहुंचे। सबने मुख्यमंत्री द्वारा परीक्षा केंद्र बदले जाने के आदेश को कार्यान्वित करने की मांग की। शिक्षा सचिव का उत्तर था, "परीक्षा केंद्रों को बदला जाना असंभव है, क्योंकि यह सिलसिला शुरू हुआ, तो लगभग ३५० परीक्षा केंद्र बदलने पड़ेंगे।"

विधायकों का कहना था, "जब परीक्षा केंद्र बदलना संभव नहीं था, तो दो माह तक उन्हें अंधेरे मे क्यों रखा गया और मुख्यमत्री को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गयी ? अब, जब तक परीक्षा केंद्र बदलने के आदेश नही जारी होंगे, हम शिक्षा सचिव का घेराव किये रहेंगे।"

विधायक यह सब इसलिए कर रहे थे, क्योंकि दो दिन पूर्व विधानसभा में शिक्षामंत्री ने लोकदल-अ के विधायक किरण पाल सिह को एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा केंद्र नही बदले जायेंगे, क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं। विधायक इस सरकारी निर्णय के विरुद्ध शिक्षा सचिव से निर्णय कराना चाहते थे।

ऐसा विधायकों ने किया : कुछ विधायक शिक्षा निदेशक बी०पी० खंडेलवाल को भी शिक्षा सचिव श्री पंत के कमरे में ले आये। बीच में विरोधी दल के नेता सत्यपाल सिह यादव ने अपने कक्ष में विधायकों, शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशक के बीच निर्णय कराने की कोशिश की। जब कोई हल न निकला, तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिये। इसी के बाद विधायकों ने शिक्षा सचिव श्री पंत और शिक्षा निदेशक श्री खंडेलवाल का घेराव शुरू कर दिया। विधायकों ने इन दोनों अधिकारियों को पहले नीचे बैठने को कहा; फिर खड़े रहने पर मजबूर किया। श्री पंत के मुंह के समक्ष जूता घुमाया। दोनों अधिकारियों के मुंह पर कालिख पोतने की धमकी दी। उन्हें पानी नहीं पीने दिया और आने वाले टेलीफोन भी 'रिसीव' नहीं करने दिये। इस दौरान कांग्रेस- इ के विधायकों—खान गुफान जाहदी और विधान परिषद सदस्य डा० हरिकृष्ण अवस्थी ने भी घेराव समाप्त करने का व्यर्थ प्रयास किया।

लगभग ५ बजे अचानक हजारों सचिवालय कर्मियों ने शिक्षा सचिव के कक्ष को घेर लिया। उस समय कक्ष में विधायक भोपाल सिह, वीरेंद्र सिह, कुशल पाल सिह, शतरुद्ध प्रकाश, रामजन्म सिह, शारदा प्रताप शुक्ल, फजलुल बारी, जवाहर सिह यादव, युवा लोकदल-अ के अध्यक्ष सुरेश गुप्त तथा ब्लाक प्रमुख अवध पाल सिह मौजूद थे। कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकलने को ललकारा ! जान बचाने के लिए विधायकों ने कक्ष को अंदर से बन्द कर लिया। उत्तेजित कर्मचारी नारे लगा रहे थे: कर्मचारी एकता जिन्दाबाद, विधायकों की गुण्डगर्दी नहीं चलेगी। उत्तेजित कर्मचारियों ने शिक्षा सचिव

विधायकों-कर्मचारियों की टकराहट का परिणाम : शिक्षा सचिव के कमरे में विधायकों द्वारा तोड़फोड़

के कक्ष की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और कक्ष के दरवाजे पर खड़े सुरक्षाकर्मियों को ढकेल कर कक्ष में प्रवेश करने के लिए जूझने लगे। इस बीच कुछ कर्मचारियों ने वहां रखे गमले तोड़ डाले। टूटी खिड़कियों के रास्ते गमलों के टुकड़ों पर पत्थरों से विधायकों को मारने लगे। विधायक जान बचाकर बाथरूम में जा छिपे। शिक्षा सचिव श्री पंत कर्मचारियों को समझाने के बहाने कक्ष से बाहर निकल गये और उनका घेराव करने वाले विधायक अंदर फंसे रह गये।

विधायक फजलुल बारी किसी तरह जान बचाकर निकल गये। जैसे ही विधायक जवाहर सिंह यादव कक्ष से बाहर निकले, क्रुद्ध कर्मचारियों ने उन्हें जमीन पर गिरा-गिरा कर पीटा और कपड़े फाड़ डाले। इसी प्रकार विधायक रामजन्म सिंह और मूलचन्द को पत्थरों से घायल कर दिया। सचिवालयकर्मी विधायकों को चोर-गुण्डों की उपाधि देकर उन्हें अश्लील गालियां दे रहे थे। उनका कहना था कि विधानसभा के अंदर यह विधायक जो गुण्डागर्दी करते हैं, वह सरकारी अधिकारियों के साथ नहीं होने दी जायेगी।

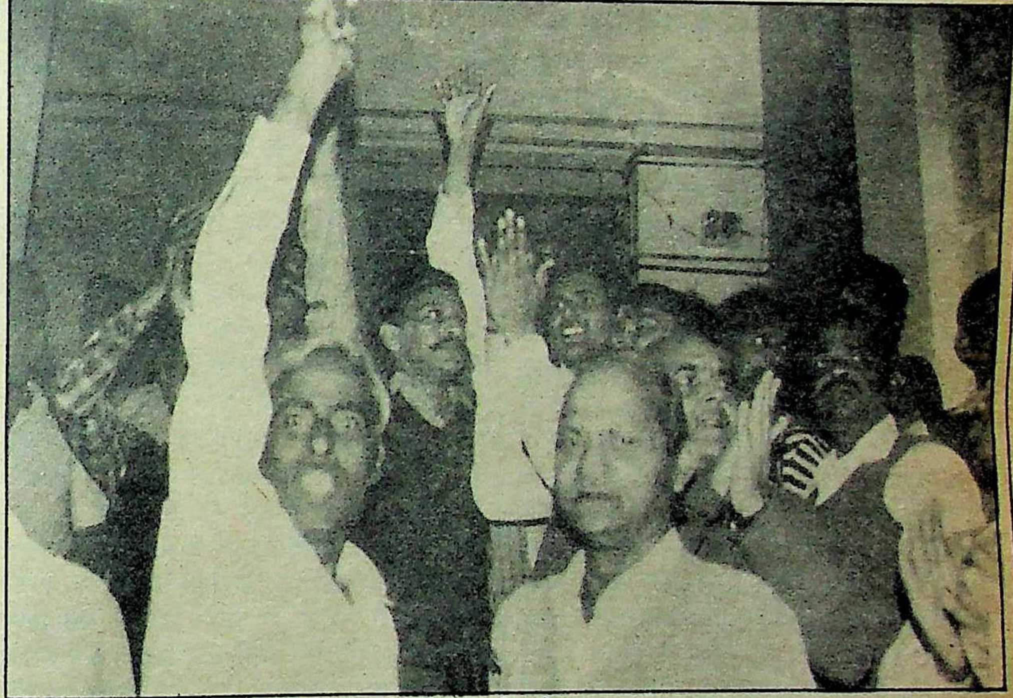

विधायकों को चुनौती : नारे लगाते हुए सचिवालय कर्मचारी

नयी व्यवस्था : इसी दौरान संसदीय कार्यमंत्री अम्मार रिजवी वहां पहुंच गये थे। उन्होंने कर्मचारियों को शांत कराने के लिए कहा, "जगदीश चन्द्र पंत जैसे सभ्य व्यक्ति के साथ जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। विधायकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे यह व्यवस्था की जायेगी कि विधायक किसी कार्य के लिए सीधे सचिवों के कक्ष में न जाकर मंत्रियों तक सीमित रहें। सचिवों से काम पड़ने पर विधायक उनसे मंत्रियों के कक्षों में ही मिलें।"

डा० अम्मार रिजवी भी कर्मचारियों को शांत नहीं करा सके। बाद मे सायं लगभग ७ बजे लखनऊ के जिला अधिकारी नरेश दयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तिलक काक, पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिंह ने फंसे हुए विधायकों को कर्मचारियों के क्रोध से बचाया। शिक्षा सचिव के निजी सहायक की रिपोर्ट के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने विधायक भोपाल सिंह, वीरेन्द्र सिंह, शारदा प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। ७ मार्च को विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने शिक्षा सचिव जगदीश चन्द्र पन्त तथा शिक्षा निदेशक बी०पी० खण्डेलवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नियाज हसन ने विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए ८ मार्च को विधानसभा में घोषणा की कि विधायकों की पिटाई की गम्भीरता से जांच होगी। दोषियों को दंड दिया जायेगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि ऐसा नहीं है कि उनके (मुख्यमंत्री) आदेशों का पालन नहीं होता है, पर इस मामले की बारीकी से जांच होगी। विधायकों का सम्मान न होना, गंभीर बात है। इसमें ढिलाई नहीं बरती जायेगी। सम्पूर्ण विपक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर असंतोष जाहिर करते हुए सदन का बहिष्कार किया।

विपक्षी सदस्यों का कहना था, "मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना सचिवों के लिए आम बात है। वास्तव में हुकूमत सरकार की नहीं, नौकरशाहों की चल रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विधानसभा में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ उठाये गये भ्रष्टाचार के मामलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे नौकरशाह निरंकुश होते जा रहे हैं।"

जनता पार्टी के नेता रेवती रमण सिंह लोकदल-ब के मुलायम सिंह यादव, लोकदल-अ के शतरुद्ध प्रकाश तथा जनमोर्चा के जगदीप सिंह बरार का कहना था, "नौकरशाही का राज अगर इसी तरह कायम रहा, तो यहां भी आंध्र प्रदेश की तरह आईएएस अधिकारियों के अपहरण की पुनरावृत्ति हो सकती है।" निश्चित तौर पर यह बयान आईएएस और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती खायी और मतभेदों का प्रमाण है। उधर आईएएस एसोसिएशन (उ०प्र०) ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के मध्य मर्यादा निर्धारित की जाये। उ०प्र० सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने भी एक-प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि कोई भी विधायक किसी सरकारी कर्मचारी से सीधे न मिल सके। अपने कार्य के संबंध में वह मुख्यमंत्री अथवा संबंधित विभाग के मंत्री से मिले। साथ ही शासकीयकर्मी के कार्य में हस्तक्षेप अपराध घोषित किया जाये। अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को अपनी राजनीतिक दृढ़ता का परिचय देते हुए जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के मध्य मर्यादा निर्धारित करनी चाहिए, ताकि यह टकराव रोका जा सके। अन्यथा कार्यपालिका और विधायिका की यह लड़ाई प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को तहसनहस कर देगी।

—निशीथ जोशी

छाया: किशन सेठ

अक्षयवर मल

पंजाब केसरी की तर्ज पर एक और हत्या

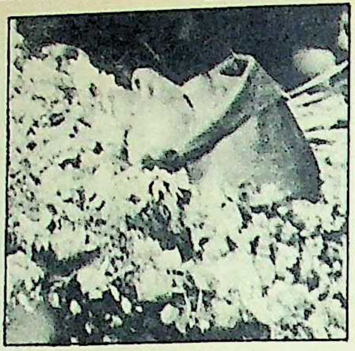

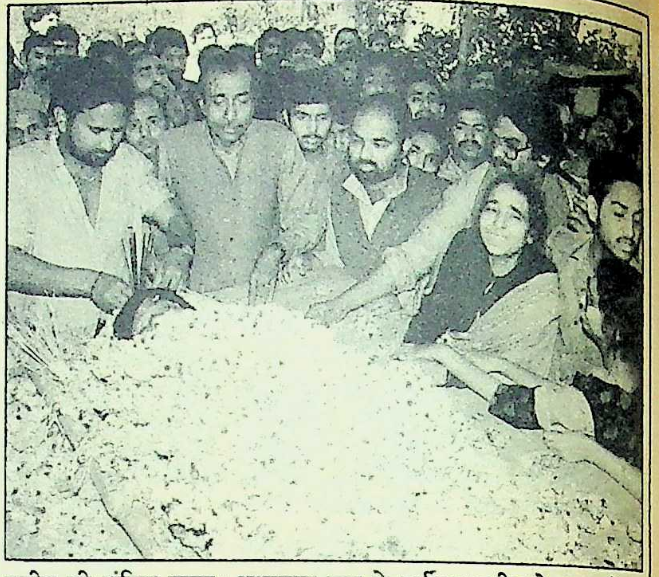

शहीद की अंतिम यात्रा : अक्षयवर मल के पार्थिव शरीर के पास शोक विह्वल परिवारजन व कार्यकर्ता

पुलिस के बरबर लाठी प्रहार से शहीद हुए लोकदल-ब के नेता अक्षयवर मल की अंतिम इच्छा थी कि विपक्ष एकजुट हो। क्या उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी?

यों पुलसिया जुल्म की खबरें आये दिन सुनने और पढ़ने को मिलती रहती हैं, लेकिन ऐन विधानसभा के सामने किसी व्यक्ति को लाठियों से पीट-पीट कर मार डालना बरबरता की तमाम सीमाओं को पार कर जाना है। गत २६ फरवरी को उ०प्र० पुलिस ने यही किया। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उसकी इसी कार्रवाई में ६२ वर्षीय समाजवादी नेता अक्षयवर मल बुरी तरह घायल हो गये, जिन्होंने अंतत: अस्पताल में दम तोड़ दिया।

घटनाक्रम : सात विपक्षी दलों के गठजोड़ से बने क्रांतिकारी मोर्चे ने २६ फरवरी, ८८ को प्रदेश के जिला मुख्यालयों और तहसीलों पर जनसमस्याओं को लेकर धरने और प्रदर्शन का आयोजन किया था। लखनऊ में लोकदल-ब के नगर अध्यक्ष अक्षयवर मल के नेतृत्व में रायल होटल स्थित पार्टी कार्यालय से सुबह ११ बजे कार्यकर्ताओं का एक जुलूस निकला। 'पुलिस जुल्म, महंगाई और भ्रष्टाचार' विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी सीधे विधानसभा भवन के सामने पहुंच गये।

यह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का प्रमाण है कि उसने जुलूस की अनुमति तो दे दी, मगर पुलिस का कोई इंतजाम नहीं किया। खास तौर पर तब, जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था।

कोई व्यवधान न देखकर प्रदर्शनकारी विधानभवन के मुख्य द्वार तक पहुंच गये। प्रदर्शनकारियों के विधानभवन के समक्ष धरना देकर बैठ जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुछ ही देर में यातायात ठप हो गया।

ड्यूटी पर तैनात एक उपनिरीक्षक ने कुछ पुलिसकर्मियों तथा पी०ए०सी० के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों के विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में श्री मल गंभीर रूप से घायल हो गये। दो दर्जन अन्य कार्यकर्ताओं को भी चोटें आयीं। इसी के साथ भगदड़ भी शुरू हो गयी। प्रदर्शनकारी वापस रायल होटल की ओर भागे। उत्तेजित लोकदल-ब के कार्यकर्ताओं ने रायल होटल चौराहे का यातायात पुलिस बूथ उलट दिया। उन्होंने पुलिस पर पथराव तथा आते-जाते वाहनों की तोड़फोड भी शुरु कर दी। पुलिस एवं प्रदर्शकारियों में लगभग आधा घंटे तक संघर्ष चलता रहा। इस बीच वहां पर पुलिस उपाधीक्षक राम सिह फोर्स के साथ आ गये। उन्होंने अक्षयवर मल सहित २८ लोगों को बंदी बना लिया।

अक्षवर मल के सिर में चोट आयी थी। खून बह रहा था। इस दृश्य की तुलना गुलाम भारत में फिरंगियों की करतूतों से की जा सकती है। उस समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी के शिकार हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब भारत आजाद है। पूलिस ने उन्हें समीपवर्ती सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। ६२ वर्षीय श्री मल प्रमुख समाजवादी नेता होने के साथ लखनऊ के सभासद भी रह चुके थे। वह इस समय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी थे।

वीपी सिंह से भेंट : घायल अक्षयवर मल के सिर पर छह टांके लगे थे। वह शाम तक होश में रहे। लाठीचार्ज से श्री मल के घायल होने की जानकारी मिलने पर शाम लगभग ५ बजे विश्वनाथ प्रताप सिंह, आरिफ मोहम्मद खां और प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री संजय सिंह के साथ उन्हें देखने अस्पताल गये।

श्री मल द्वारा शुक्रिया अदा किये जाने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनसे कहा, "आप बधाई के काबिल हैं, जो आपने जालिम सरकार से लड़ते हुए बहादुरी पूर्वक जुलूस का नेतृत्व किया।" बातचीत के दौरान श्री सिंह ने कहा, "मैं तो चाहता हूं, सारा विपक्ष एक हो जाये, तो व्यवस्था ही बदल दी जाये।" श्री मल ने हामी भरते हुए जवाब दिया था, "मैं आखिरी दम तक यही कोशिश करूंगा कि सब एकजुट हो जायें।"

थोड़ी देर बाद श्री मल अचेत हो गये। देखते-ही देखते उन्होंने सदा के लिए आंख बंद कर ली।

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस में अक्षयवर मल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट में लिखाया गया कि उपनिरीक्षक एन०पी० गौतम ने कुछ पुलिसकर्मियों व पी०ए०सी० के जवानों के साथ अक्षयवर मल की लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

श्री मल का पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज में तीन चिकित्सकों के एक पैनल द्वारा किया गया। अगले दिन उनका शव एक विशाल जुलूस के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ उनके आवास ले जाया गया। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे।

शवयात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न कोने से काफी संख्या में लोग आये थे। जुलूस के साथ पुलिस का एक विशाल काफिला चल रहा था। दिवंगत नेता के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र की सभी दुकानें बंद थी।

एक मार्च को विधानसभा में विपक्ष के शोर-शराबे व हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री डा० अम्मार रिजवी ने जब यह कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्री मल की मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है, तो लोकदल-ब के प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 'सरकारी रिपोर्ट' करार देते हुए उस पर संदेह प्रकट किया। दूसरी ओर डा० रिजवी बार-बार यह कहते रहे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि श्री मल की मृत्यु सिर की चोट के कारण नहीं हुई है।

नेता विरोधी दल सत्यपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को सदन में बुलाये जाने की मांग की। उत्तेजित विपक्षियों ने इतने में सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिये। डा० अम्मार रिजवी द्वारा न्यायिक जांच कराने की घोषणा के बाद सदन की कार्रवाही स्थगित कर दी गयी।

—स्वदेश कुमार

छाया : राजेंद्र कुमार

हाकी

क्या गुल खिलायेगी शाहिद की वापसी ?

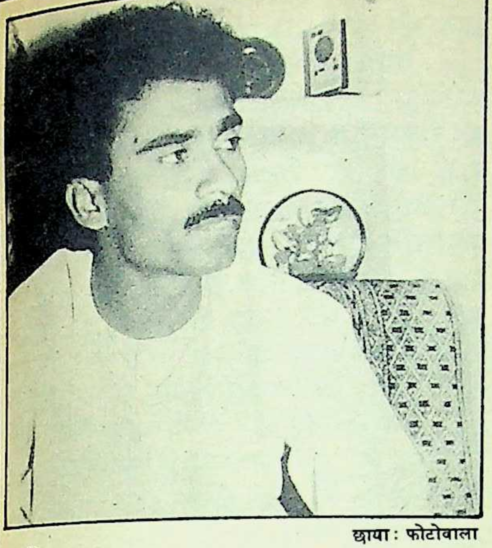

छाया : फोटोवाला

सोल ओलंपिक भारत के लिए आखिरी मौका है। यदि वह सोल में अपनी काबिलीयत सिद्ध नहीं कर सका, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों से उसका पत्ता लगभग साफ हो जायेगा। उसकी असफलता का सीधा-सा अर्थ है—भारतीय हाकी की ताबूत में आखिरी कील का ठुकना। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मात्र हिस्सा लेने के लिए भी उसे नये सिरे से अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी जो कि एक लंबी प्रक्रिया होगी और एक बार डूबने के बाद भारतीय हाकी को उबरने में बरसों लग सकते हैं। यों भारत को सोल ओलंपिक में भी खेलने से मना किया जा सकता था, क्योंकि वह उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। यह एशियाई हाकी संघ के निवेदन और अंतरराष्ट्रीय हाकी संघ की मेहरबानी ही थी जो उसे ओलंपिक में भाग लेना नसीब हो रहा है। अजब विडंबना है कि कभी ओलंपिक चैंपियन रहने वाली टीम अब ओलंपिक में खेलने भर के लिए किसी की मेहरबानी पर निर्भर है।

बहरहाल, लगता है खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं ने इस खतरे की घंटी को ध्यान से सुन लिया है और वे यह मौका किसी भी हालत में गवाना नहीं चाहते हैं। हाल में संपन्न हुए रंगास्वामी कप में खिलाड़ियों ने जिस गंभीरता से हाकी खेली, उससे तो यही अंदाजा मिलता है। कम-से-कम फाइनल मैच में, जिसमें रेलवे का मुकाबला इंडियन एयरलाइंस से हुआ, यही बात देखने को मिली। यद्यपि रेलवे ने यह टूर्नामेंट जीत लिया, मगर मुकाबला काफी रोमांचक रहा, खास तौर पर मध्यांतर के बाद का। व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय खिलाड़ियों ने टीम वर्क को तरजीह दी जो कि एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

रंगास्वामी कप के फाइनल के ही दिन २६ सदस्यीय टीम की घोषणा हुई। चयनकर्ताओं ने कोई खतरा न उठाते हुए काफी संतुलित टीम का चयन करने का प्रयास किया है। हालांकि इन २६ खिलाड़ियों में से आखिरी १४ का चयन होना बाकी है, मगर फिर भी ऐसा कोई नाम इस सूची में छूटा नहीं है जिसके लिए बोर्ड पर उंगली उठायी जा सके।

सबसे स्वागत योग्य कदम है पूर्व कप्तान मोहम्मद शाहिद और मेरविन फर्नांडिस की वापसी। शाहिद को यह कहकर टीम से बाहर कर दिया गया था कि वह बहुत ज्यादा ड्रिब्लिग़ करते हैं और व्यक्तिगत प्रयासों पर उनका ध्यान ज्यादा लगा रहता है। लेकिन राष्ट्रीय हाकी (रंगास्वामी कप) में ऐसी कोई बात नजर नहीं आयी। उनकी ड्रिब्लिग बेमिसाल थी और हर प्रयास टीम वर्क का एक उम्दा नमूना था। शाहिद इस समय विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं। इतने दिनों तक टीम से उनका बाहर रहना निश्चित रूप से भारतीय हाकी के लिए अच्छा नहीं था। उनके आने से एक बेहतरीन फारवर्ड की कमी पूरी होगी और भारतीय टीम में नये उत्साह का संचार होगा।

ढाका में गलत व्यवहार के लिए अंतरराष्ट्रीय हाकी संघ ने मेरविन फर्नांडिस पर पांच वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हाल में वह घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया था। यह अवधि अब खतम हो चुकी है, मगर मेरविन के वापस आने की वजह है उनकी शानदार फार्म। राष्ट्रीय हाकी में उन्होंने एयरलाइंस के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उनकी चुस्ती-फुर्ती, गेंद पर नियंत्रण और 'मूव' बनाने का तरीका सब कुछ काबिले तारीफ था। रेलवे के मुकाबले ३-० से पिछड़ने के बाद उनकी ही बदौलत एयरलाइंस की वापसी मैच में हुई थी। इस तरह उनकी वापसी भी भारतीय टीम में नयी जान ला सकती है।

२६ सदस्यीय टीम में तीन बड़े नाम नहीं है। थोइबा सिंह, टिक्कन सिंह और राम प्रकाश सिंह को बाहर कर दिया गया है। थोइबा और टिक्कन का प्रदर्शन हाल में बहुत अच्छा नहीं रहा था, इसलिए उनका निकाला जाना ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन युवा खिलाड़ी राम प्रकाश सिंह का टीम में न होना खल सकता है। गोलकीपर आर०एस० रावत की भी छुट्टी कर दी गयी है। जेम्स केरकेटा की जगह जफर इकबाल को मौका देना बेहतर होता।

प्रशिक्षण : अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर लेना भर पर्याप्त नहीं है। अच्छे प्रदर्शन के लिए इससे भी जरूरी बात है उन्हें अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराना। बदकिस्मती से हमारे यहां आग लगने पर कुंआ खोदने का रिवाज है। रिलायंस कप के पहले भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षण के मामले में भी यही लापरवाही बरती गयी थी। हाकी के मामले में एक और दिक्कत यह है कि अब उसे दूसरे दर्जे का खेल समझा जाने लगा है और क्रिकेट के मुकाबले नाम मात्र की ही सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं।

सोल ओलंपिक को अब केवल छह महीने (सितंबर) शेष रह गये हैं। इस थोड़े से समय में एक अच्छी टीम खड़ी कर पाना एक चुनौती भरा काम है। यदि अभी से प्रशिक्षण का काम शुरू न हुआ, तो किसी अच्छे परिणाम की आशा करना बेमानी होगा। खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब अधिकतर खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ पर खेलने का अभ्यास नहीं है। राष्ट्रीय हाकी में यह कमजोरी और भी खुलकर सामने आ गयी। ज्यादातर खिलाड़ी गेंद पर से अपना नियंत्रण खो बैठते थे और अकसर गेंद उनसे ज्यादा तेज निकल जाती थी। एस्ट्रोटर्फ में खेल बहुत तेज होता है। भारत में एस्ट्रोटर्फ के मैदान भी गिने-चुने हैं। ऐसी स्थिति में हर खिलाड़ी से यह आशा करना कि वह एस्ट्रोटर्फ पर बेहतरीन प्रदर्शन करे, ठीक नहीं होगा। हां यह जरूर हो सकता है कि चुने हुए २६ खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ के अनुकूल ढालने के लिए हर संभव कोशिशें की जायें। इसके लिए जरूरी है कि वगैर वक्त जाया किये अभी से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होने लगे।

भारतीय हाकी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है गलत निशाने। अच्छे मूव बनाने और गोल के मुहाने तक पहुंच जाने के बावजूद हमारे खिलाड़ी गेंद गोल में नहीं डाल पाते। पेनाल्टी कार्नर बरबाद करने के मामले में भी हम सबसे आगे हैं। इन सभी कमजोरियों का एकमात्र इलाज है जोरदार प्रशिक्षण।

भारतीय हाकी काफ़ी अरसे से इस पसोपेश में भी रही है कि की कौन सी शैली अपनायी जाये। हाकी पर बढ़ते यूरोपीय प्रभुत्व से प्रभावित होकर उसने ३-३-३-१ की यूरोपीय शैली अपना ली थी, मगर इससे भी उसे कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एशियाई शैली (५-३-२-१) से खेलते हुए बड़ी उपलब्धियां न सही, मगर छोटी-छोटी सफलताएं जरूर हासिल की हैं। हाल में उसने लखनऊ में इंदिरा गांधी मेमोरियल हाकी में भी इसी शैली में खेलकर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय हाकी में भी एशियाई शैली का प्रभुत्व साफ नजर आया। इस लिहाज से यह दलील दी जा रही है कि भारतीय परिस्थितियों में एशियाई शैली ही भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह अलग बात है कि भारत केवल इसी बूते पर अपना विश्व विजयी मुकुट दोबारा हासिल नहीं कर सकता है। इसके लिए जरूरत है निचले स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जिससे प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिल सके।

—मुकेश कुमार

कर्ज का कसता फंदा

संसद में बजट पेश होने के एक दिन बाद मुझे कहा गया कि मैं कर्मचारियों के एक समूह को बजट के बारे में बताऊं। मेरी समझ से उनमें से किसी को भी यह मालूम नहीं था कि बचत और घाटे में या व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या फर्क है। बहरहाल, मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी, इसलिए मैंने कहना शुरू किया कि सरकार अगले साल ७५ हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि में से दो-तिहाई रोजमर्रा का खर्च चलाने और एक तिहाई से कुछ ज्यादा विकास के नाम पर खर्च होगा। कमरे में बिलकुल शांति छायी। हुई थी। मुझे लग रहा था कि अब वे पूछेंगे कि विकास का मतलब क्या होता है? जैसा कि इस समय हर कोई पूछ रहा है, लेकिन उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठ रहे थे।

आखिरी बेंच से एक व्यक्ति ने पूछा, "७५ हजार करोड़ रुपए कितने होते हैं?" बैठक के पहले मैं उस व्यक्ति से मिल चुका था। उसने मुझे बताया था कि वह एक मालगोदाम में काम करता है और २० रुपए तक रोज कमा लेता है। यह अच्छा प्रश्न था, मगर इसका उत्तर जरा मुश्किल था। मैं सीधे-सीधे उसे और उसके साथियों को नहीं बता सकता था कि ७५ हजार करोड़ रुपए कितने होते हैं। इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने उन्हें बताया कि सरकार हर दिन लगभग २०० करोड़ रुपए खर्च करेगी और यदि इससे भी छोटे आंकड़े चाहिए, तो वह १० करोड़ रुपए प्रति घंटे खर्च करेगी। आखिरकार, मैंने मन-ही-मन सोचा कि मुद्रास्फीति के इस युग में हर व्यक्ति जानता है या हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि १ करोड़ कितना होता है। बातचीत के बाद वह व्यक्ति मेरे पास फिर आया और बोला कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया है। उसने कहा कि कृपया मुझे समझायें कि कोई एक घंटे में दस करोड़ या एक ही करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकता है।

अब मैंने महसूस किया कि लोग बजट को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? वे समझते हैं कि बजट आमदनी और खर्चे के बारे में कुछ है, लेकिन उनकी दरिद्र जिंदगी से उसका दूर का वास्ता है।

अतः घर लौटकर मैंने हिसाब लगाया। मान लीजिए सरकार हर आदमी, औरत और बच्चे को साल की शुरुआत में एक-एक हजार रुपए देती है और उनसे एक साल में पूरा खर्च करने के लिए कहती है। यह कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह राशि ७५ हजार करोड़ हो जाती है जो कि सरकार एक साल में खर्च करती है या अगले साल खर्च करेगी।

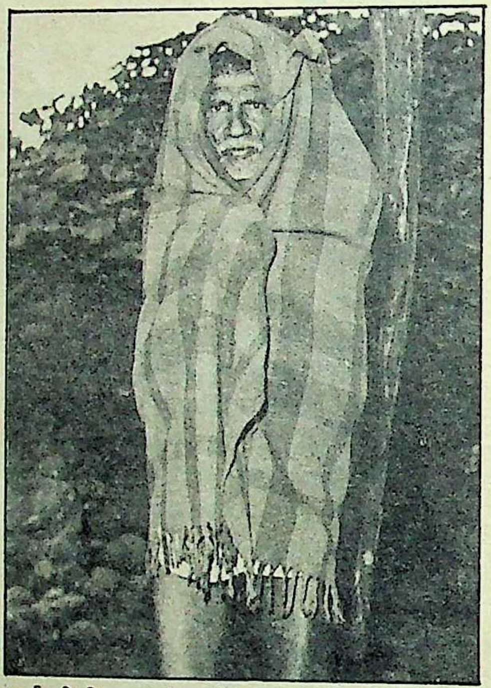

कर्ज की ठिठुरन और बढ़ेगी

इसे एक दूसरे तरीके से समझते हैं। भारत में लगभग सात लाख गांव हैं और वे एक लाख करोड़ व्यय हर साल या एक गांव १५ लाख रुपए हर साल कमाता है। इस तरह ६० गांव जितना एक साल में कमाते हैं, उतना सरकार एक घंटे में खर्च कर रही होंगी। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सरकार हर दिन १५,००० गांवों को निगल जाती है। जब मैंने एक बार चौधरी चरणसिंह को यह बताया था, तो उन्होंने कहा था, "मुझे पता है वे हमें निगल रहे हैं, मगर यह पता नहीं कि उनकी भूख इतनी बड़ी है।"

जितनी कमाई हम और आप करते हैं, वह सरकार कुछ ही सैकेड़ों में उड़ा देती है। साल में ५०,००० की कमाई करने वाले किसी व्यक्ति की आमदनी के बराबर की राशि दिल्ली के नार्थ ब्लाक (मंत्रियों के दफ्तर) के बाबू दो सेकेंड से भी कम समय में उड़ा देते हैं। मालगोदामों में काम करने वाले उन मित्रों की आय के बराबर रकम, जो जानना चाहते हैं कि ७५ हजार करोड़ कितने होते हैं, ये बाबू एक चौथाई सेकेंड में ही फूंक देते हैं। हर सरकार के लिए काम करते हैं—वे भी जो सोचते हैं कि वे अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कमाई का चौथाई हिस्सा किसी भी तरीके से सरकार प्राप्त कर लेती है और उसका बहुत कम वापस लौटाती है।

आखिर सरकार इतनी ज्यादा राशि का क्या करती है? कुछ साल पहले तक एक तिहाई राशि वह रोजमर्रा के कामों पर खर्च करती थी, लेकिन बाकी की दो तिहाई राशि वह उन नयी परियोजनाओं में लगाती थी, जिससे आय और परिसंपत्ति (एसेट्स) बढ़े। अब यह अनुपात उलट गया है। दो तिहाई राशि अब प्रशासनिक कार्यों पर खर्च होती है और केवल एक तिहाई ही विकास कार्यों के लिए बचती है। फिर भी सरकार की भूख बढ़ती गयी और धीरे-धीरे धन की कमी पड़ती गयी। जब यह कमी बहुत ज्यादा बढ़ गयी, तो उसने नोट छापना शुरू कर दिया। यही बजट घाटा कहलाता है।

घाटे के बजट काफी अरसे से पेश हो रहे हैं, लेकिन अब यह घाटा चालू खातों में भी होने लगा है। यह उसी तरह है, जैसे कोई मकान किराया और रसोई खर्च चलाने के लिए कर्ज ले। इस साल चालू खातों का बजट दस करोड़ होगा जो कि सरकार के 'रसोई खर्च' का २० प्रतिशत होगा। १९७८-७९ तक कोई घाटा नहीं था और मूल्य भी नियंत्रण में थे। यहां एक बात और है। जब आप चालू खर्चों के लिए उधार लेते हैं या जब पूंजी खाते से चालू खाते में स्थानांतरित करते हैं, तब वास्तव में आप पूंजी नष्ट कर रहे होते हैं और निश्चित रूप से यही हो रहा है।

जब आप उधार लेते हैं, तो कर्ज में डूबते हैं—चाहे आप उससे परिसंपत्ति ही क्यों न जुटा रहे हों। कुछ साल पहले तक हमारे ऊपर कुल कर्ज प्रति वर्ष दस हजार करोड़ तक चढ़ गया था। अब यह बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सरकार अब बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। अगले साल तक ब्याज दर ही बढ़कर १४ हजार करोड़ हो जायेगी। चार साल पहले इसकी आधी राशि थी और २० साल पहले केवल एक हजार करोड़ रुपए थी। १९६०-६१ में हमारे ऊपर कुल कर्ज ७००० करोड़ था और उस पर १६२ करोड़ रुपए ब्याज लगता था।

जब आप उधार-पर-उधार लेते जाते हैं (क्योंकि आप अपनी परिसंपत्ति का कायदे से प्रबंध नहीं कर रहे, इसलिए आपको बहुत कम आय हो रही है), तो उसी रफ्तार से आपको ब्याज भी देना होता है। इस तरह एक दिन, ऐसा आयेगा कि जो उधार लिया, उसे भी चुकता नहीं कर पायेंगे। यह 'कर्ज का जाल कहलाता हैं', जब आपको ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है और भविष्य में पूंजीनिवेश करने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अमरीका में यही हुआ है। वहां के तथाकथित 'बनाना रिपब्लिक' (जिन देशों की अर्थव्यवस्था फलों और पर्यटन पर टिकी है) भारी कर्ज में डूब गये हैं और अब अपने बैंकों से कर्ज लेकर भी ब्याज की रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।

अब हम इस 'कर्ज के जाल' से कितनी दूर हैं? वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अपने बजट भाषण में 'कर्ज' शब्द का नाम भी नहीं लिया, जिससे ऐसा लगता है, मानो सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन

सरकार से बचे, तो इनको मिले !

जब तक आर्थिक नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होता, 'कर्ज-जाल' का शिकंजा कसता जायेगा। तमाम हिसाब लगाने के बाद मैंने पाया है कि जब हम २१वीं सदी में प्रवेश कर रहे होंगे, तो 'कर्ज-जाल' और भी व्यापक हो जायेगा। सन २००१ में हम पर १२ लाख करोड़ रुपए का कर्ज होगा और हमें एक लाख करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे, जबकि ब्याज की रकम एक लाख, एक हजार करोड़ रुपए होगी। मुझे मालूम नहीं कि इन आंकड़ों का आपके लिए क्या मतलब होगा, मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज से १२ साल बाद हमारे ऊपर कर्ज वर्तमान राष्ट्रीय आय का चार गुना हो जायेगा। ब्याज की रकम भी बढ़कर वर्तमान राष्ट्रीय आय की तिहाई राशि के बराबर हो जायेगी। संभव है, ये आंकड़े समझ में न आ रहे हों, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे कंधों पर कर्ज का बड़ा भार होगा और औसतन प्रत्येक भारतवासी १२ हजार रुपए का कर्जदार हो जायेगा।

हमसे ये सारे पक्ष चतुराई पूर्वक छुपाये गये। हमें बताया गया कि किसानों को कई रियायतें दी गयी हैं। बैंकों से ऋण देने आदि में भी उन्हें सुविधा की गयी है, ऐसी घोषणाएं सरकार ने की। किसान और खेतों में काम करनेवाले मजदूर देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई से भी ज्यादा पैदा करते हैं। इसके बावजूद वे सबसे गरीब हैं और यहां तक कि फैक्ट्री और बैंकों में काम करनेवाले मजदूरों से भी बदतर हालत है, उनकी। इनमें से कुछ 'कुलक' कहे जाते हैं। 'कुलक', रूसी शब्द है। इसका उपयोग स्तालिन ने क्रांति विरोधी किसानों के लिए किया था। ये कुलक सोवियत क्रांति के दौरान लाखों की तादाद में मारे गये थे। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अमीर किसान सबसे गरीब उद्योगपति की तुलना में भी गरीब है और ऐसा अन्य किसी भी देश में नहीं है। १९५०-५१ में किसानों और शहरी व्यापारियों की आय में कोई खास अन्तर नहीं था। शहरी व्यापारी किसान के मुकाबले डेढ़ गुना ज्यादा कमाता था जो कि ज्यादा अंतर नहीं माना जाता था। १९६०-६१ में यह अंतर बढ़कर दुगना और १९७०-७१ में ढाई गुना हो गया। १९८०-८१ में शहरी आय ग्रामीण आय की तीन गुनी हो गयी है और जिस दर से यह अंतर बढ़ रहा है, अगले दो वर्षों में यह अनुपात ४:१ का हो जायेगा।

पिछले चालीस सालों में किसानों की औसत आय शहरी व्यापारियों के मुकाबले चौथाई गिर गयी है। यदि एक फैक्ट्री मजदूर १००० रुपए महीने कमाता है, तो किसान या खेतिहर मजदूर २५० रुपए महीने से ज्यादा नहीं पाता। चालीस साल पहले मजदूर महीने में १५० रुपए और किसान १०० रुपए पाता था जो कि आज के मुकाबले बड़ा अंतर नहीं था। अब किसानों की मांग है कि यह अंतर कम किया जाये। यदि ऐसा संभव न हो, तो कम-से-कम इस अंतर को बढ़ने से रोका जाये।

विकसित देशों में आय में अंतर बहुत कम है या भारत में ४० साल पहले जितना है। जापान में तो स्थिति उलटी है। वहां के किसान और खेतिहर मजदूर फैक्ट्री मजदूरों से ज़्यादा कमाते हैं। सरकारी नीति के तहत किसानों को हर तरह की सब्सिडी (अनुपूरक सहायता राशि) प्राप्त है। किसानों से वहां २० रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीदा जाता है, मगर बाजार में बिकता है ६ रुपए किलो। अमरीका की तरह जापान में भी कृषि को भारी सब्सिडी मिली हुई है। आय में ज्यादा अंतर समाजिक दृष्टि से भी हानिप्रद है।

इस तरह से बजट की मीमांसा करने के बाद पूछा जा सकता है कि इस साल सरकार ने किसानों को क्या दिया? अब वे थोड़े आसान तरीकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और सस्ती दरों पर खाद। बरसों के शोषण के बाद ये सुविधाएं ज्यादा नहीं हैं और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो खादों पर दी जा रही सब्सिडी को कम करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विश्व बैंक ऐसा चाहता है। आखिर, विश्व बैंक जापान से सब्सिडी कम करने के लिए क्यों नहीं कहता? क्योंकि जापान विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेता है।

हमारे अर्थशास्त्री अब एक कदम आगे बढ़ गये हैं। वे अब किसानों पर भी आयकर लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ साथ-ही-साथ वह शहरी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आयकर सीमा बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। यहां यह संदेह होता है कि क्या हमारे अर्थशास्त्री यह भी नहीं जानते कि खेती कैसे होती है और किस तरह से किसान अपनी जिंदगी काट रहा है?

यह आपको पूछना चाहिए कि बजट घाटा, राष्ट्रीय कर्ज और किसानों की आय में क्या संबंध है? इनका बहुत नजदीकी रिश्ता है। किसानों की आय बहुत कम है, क्योंकि कृषि ज्यादा कमाई नहीं देती और यह इसलिए, क्योंकि कृषि में बहुत कम पूंजीनिवेश की जा रही है। उद्योगों और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निवेश किया जा रहा है। ऐसा इस गलतफहमी के कारण है कि किसानों की रफ्तार कम है और आधुनिकता के लिए उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। वास्तव में कृषि उत्पाद की कम कीमत देकर आमदनी को हमने किसानी से उद्योगों में स्थानांरित कर दिया है और जबकि कृषि से हमारी बचत पर्याप्त नहीं है। हमने देश के अंदर और विदेशों से भारी मात्रा में कर्ज ले लिया है। अब हम जितना कमाते हैं, उसका आधा ब्याज चुकाने में चला जाता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है, जिसे हमने खुद तैयार किया है।

बजट में जो सुविधाएं किसानों को देने की बात कही गयी है, वास्तव में वह घूस है। सरकार ने आकर्षक राजनीति खेली है, मगर आर्थिक नीति गडबडा गयी है। दोनों को मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके नियम अलग-अलग हैं। अर्थशास्त्र बहुत कड़ा स्वामी है, जिसको आप जितना सौंपते हैं उसकी तुलना में बहुत कम वापस पाते हैं।

हमने कृषि को अनदेखा किया है, क्योंकि इसे हमने आधुनिक क्षेत्र नहीं माना। ऐसा सोवियत क्रांति का बिना सोचे समझे अनुसरण करने से हुआ। १९६० में सोवियत अर्थव्यवस्था एक समय विश्व में दूसरे नंबर पर थी। ख्रुचेव ने तब कहा था कि वह अमरीकी पूंजीवाद को दफना देंगे, लेकिन उसके बाद रूस दोबारा ऐसी बात कहने की स्थिति में नहीं रहा। अब वह जापान से भी नीचे है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जापान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मिखाइल गोर्बाचेव खुन कह रहे हैं कि सोवियत अर्थ-व्यवस्था गड़बड़ा गयी है। क्रांति के ७० वर्ष बाद भी रूस खाद्यान्न के मामले में अमरीका पर निर्भर है। उसके अनुसार ऐसा सूखे के कारण हुआ, लेकिन यह बहानामात्र है।

जय दुबाशी

'४० साल' पर विवाद क्यों ?

जज यानी न्याय की मूर्ति जो बिना किसी सबूत के किसी अपराधी को एक दिन की भी सजा नहीं देता, यदि वह जज बिना किसी प्रमाण के समाज के किसी वर्ग पर आक्षेप करता है, तो निश्चित ही आपत्तिजनक माना जा सकता है। क्या लखनऊ के सिविल जज़ श्री चंद्रभूषण पांडेय ने ऐसा किया है ? यह सवाल उनकी १२० पृष्ठीय छोटी-सी पुस्तक '४० साल' के संदर्भ में उठा है। जिसको लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के वकील उनके विरुद्ध आंदोलनरत हैं। यों तो यह लघु पुस्तिका पांडेयजी ने पूरे देश का ध्यान सुद्धू-सरीखे हरिजनों की ओर दिलाने के लिए लिखी है, लेकिन उसी सुद्धू के बहाने मेरा गांव, मेरा देश, तरक्की, पहचान, वायदे, एक झलक में शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा, राजनीति, न्यायपालिका, प्रेस, सरकारी कर्मचारी, गांव की ज़िंदगी के सभी पक्षों पर चलताऊ ढंग से टिप्पणियां की हैं।

यद्यपि कुछ वैर्गों को छोड़कर प्राय: सभी वर्गों को उन्होंने अपने तीर का निशाना बनाया है, लेकिन वकील कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं। अपने गुस्से का इजहार वकीलों ने ४ फरवरी को पांडेयजी का पुतला जलाकर किया, साथ ही इस पुस्तक की प्रतियां जलायीं तथा पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ठप करने की धमकी भी दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के वकीलों सहित निचली अदालतों के वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सभाएं आयोजित कर चंद्रभूषण पांडेय को गिरफ्तार करने, उनकी पुस्तक को प्रतिबंधित करने तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। लखनऊ के वकीलों ने देश भर के बार एसोसिएशनों को भी प्रस्ताव भेजे। फलस्वरूप कानपुर, रायबरेली, फैजाबाद सहित प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों के वकीलों ने एक-एक दिन की हड़ताल कर पुस्तक की प्रतियां जलाकर सचाई का दहन किया। वकील तब जाकर ठंडे हुए, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमिताभ मुखर्जी ने चंद्रभूषण पांडेय को ६ सप्ताह की छुट्टी पर जाने को कहा। और वह १० फरवरी से अवकाश पर चले गये। लेकिन वकीलों ने हड़ताल १२ फरवरी को तब वापस ली जब उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने वकीलों के प्रतिनिधियों को यह बताया कि श्री पांडेय का स्थानांतरण कर दिया गया है और मामले की जांच उच्च नयायालय के अतिरिक्त निबंधक भंवर सिह को सौंप दी गयी है।

विवादास्पद अंश: प्रश्न उठता है कि '४० साल' नामक पुस्तक में ऐसा क्या है, जिस पर वकील इतने खफा हैं। पुस्तक के पृष्ठ सं० ५८ से ६० का वह विवादास्पद अंश द्रष्टव्य है:

"...वकील बनने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है इस लिए जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो कोई काम या धंधा नहीं पाते हैं, वे भी वकील बनते जा रहे हैं। वकीलों की इस भीड़ ने वकालत की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। उस समय वकील अपने पेशे, अपने आचरण और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते थे। मुवक्किल मिले या न मिले, वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते थे। आज तमाम वकील जिन्हें मुवक्किल नहीं मिलते, मुवक्किल पाने के लिए झूठे मुकदमे तैयार कराते हैं। मुकदमों की फाइलें गायब कराते हैं। पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। डाक्टर से मिलकर फर्जी चोट रिपोर्ट तैयार कराते हैं। झूठे खर्चे बताकर पैसा ऐंठते हैं। फर्जी जमानतें दाखिल करते हैं। फर्जी कागज तैयार करते हैं। झूठी पहचान करते हैं। सही राय नहीं देते। राय मांगने जाइये, तो मुकदमा दाखिल कराते हैं। मुकदमे में तारीख-पर-तारीख डलवाते हैं ताकि उनको पैसा मिलता रहे। पक्षों में आपसी सुलह नहीं होने देते। न्यायाधीशों के नाम पर पैसा लेते हैं। अधिकारियों, न्यायालयों को तरह-तरह का लालच देकर उन्हें मिलानें की कोशिश करते हैं। ऐसे वकीलों की कोई फीस नहीं है। जितना मुवक्किल से निकल पाये, वही उनकी फीस है। अधिकारियों एवं न्यायाधीशों से अपने संबंधों को बताकर वे मनमाना पैसा ऐंठते हैं। मोटी रकमें लेकर काम कराने की गारंटी देते हैं। काम न होने पर बड़ी मुश्किल से पैसा लौटाते हैं। नामी-गिरामी बड़े वकील सामाजिक न्याय, समता, वैयक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर धन पशुओं, मशहूर अपराधियों की वकालत में ही व्यस्त रहते हैं। ...आज वकीलों का एक तपका प्रत्येक न्यायालयों में ऐसा बन गया है जो न्यायाधीशों का सम्मान नहीं करता है, कार्य कराने के लिए उन्हें धमकाता है, उन्हें डराने के लिए झूठी शिकायतें करते हैं। ...आज वकीलों में एक वर्ग हमेशा हड़ताल की फिराक में जैसे बैठा रहता है। इस हडताली वर्ग पर किसी का कोई असर नहीं है। चाहे, अनचाहे हर वकील को उसका समर्थन करना ही पड़ता है।"

पांडेयजी ने प्राय: सभी वर्गों के बारे में कुछ-न-कुछ टिप्पणी की है, लेकिन आक्रोश में केवल वकील ही क्यों आये, इस पर पांडेयजी का कहना है, "पुस्तक मैंने आम आदमी की हैसियत से लिखी है। चूंकि मैं न्यायाधीश भी हूं, इसलिए हो सकता है कि वकीलों ने यह महसूस किया हो कि मैंने उन्हीं को इंगित किया है, जबकि ऐसी बात नहीं है।" वह बताते हैं, "आम वकील नाराज नहीं है। करीब-करीब सभी जिले के वकीलों ने समर्थन में मुझे चिट्ठियां भेजी हैं। फैजाबाद, बिजनौर के वकीलों ने तो बाक़ायदा प्रस्ताव पारित कर बधाई दी है। देश भर से उसके समर्थन में चिट्ठियां आ रही हैं।" जबकि लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलशन राज छाबड़ा का कहना है, "न्यायाधीश श्री पांडेय ने बहुत गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियां की हैं। बिना तथ्य व प्रमाण के वकील समुदाय पर लांछन लगाने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश की कुरसी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।" कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रिया लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अवस्थी ने भी व्यक्त की है, "वकीलों के आचरण पर आक्षेप लगाने के पहले न्यायाधीशों को खुद अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। इस तरह की अशोभनीय हरकत एक न्यायाधीश को शोभा नहीं देती।" लेकिन लोकदल-अ के प्रादेशिक महामंत्री मोहन सिंह ने इस पुस्तक को निरापद बताते हुए कहा है, "जज पांडेय ने अपनी पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिस पर इतना बड़ा तूफान खड़ा किया जाये। लेखक ने तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का सांगोपांग चित्रण किया है। उन्हें प्रताड़ित करना निंदनीय है।"

बहरहाल पांडेय ने यह पुस्तक लिखकर कई सवाल खड़े कर दिये हैं। इनमें एक प्रमुख सवाल है कि क्या श्री पांडेय ने सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन किया है ? यदि जांच के बाद परिणाम पांडेय के विरुद्ध गया, तो क्या न्यायिक सेवा संघ उस मामले को गंभीरता से लेगा ? और यदि जांच का फैसला वकीलों के पक्ष में नहीं गया, तो क्या वकील पुन: आंदोलन छेड़ेंगे ?

परिणाम चाहे जो भी हो चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, "इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नेवाला वकील समुदाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए आंदोलन कर रहा है।" वह आगे कहते हैं, "यदि व्यवस्था में लगे लोग ही सचाई नहीं लिखेंगे, तो सुधार कैसे होगा ? व्यवस्था में लगे लोगों के सच बोलने-लिखने पर रोक लगना आत्मघाती होगा। आज ४० वर्षों से जो ऐसी स्थिति आयी है उसका कारण यही है कि व्यवस्था में लगे लोग बोले नहीं। रोटी कमाना ही मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि देश तथा देश के आम लोगों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में यह पहल की है। यदि यह जुर्म है, तो हर परिणाम भुगतने को तैयार हूं।"

—सुरेश द्विवेदी

ON TIME
PM 07:10
07
PM 08:40
ROBOTEX
Texla

आ गया टैली-जगत में अनदेखी विशेषताओं का अस्त्र-शस्त्र लेकर...

टेली-तकनीक की नयी सीमाओं को लांघता, आ पहुँचा है रोबोटेक्स – एक ऐसा कलर टीवी जो उन्नत विशिष्टताओं के शस्त्रागार की ताकत पर टेली-जगत में अपना विजय-पताका फहरा रहा है।

रोबोटेक्स... तकनीकी जादूगरी और नये रूप-ओ-अंदाज़ का बेजोड़ समन्वय जिसे आप,एक 28 बटन वाले रिमोट कंट्रोल यंत्र के ज़रिये, दूर बैठे, उंगली मात्र के स्पर्श से जागृत कर सकते हैं.

- अपने आप चालू व बंद होने की सुविधा ताकि आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखना न भूलें.
- स्क्रीन पर सुबह-शाम का वक्त दर्शाने वाला विशेष डिजिटल घड़ी.
- स्क्रीन पर 6 रंगों में 11 टीवी कार्यों का डिसप्ले – जैसे ट्यूनिंग की बारीकी, चालू व बंद होने का समय, तथा आवाज़, चमक, रंग-संतुलन व कॉन्ट्रास्ट लैवल आदि.
- स्लीप-टाइमर सुविधा, जिस से, अगर आप चाहें तो टीवी खुद-ब-खुद 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, या 10 मिनट के बाद बंद हो सकता है।
- अती-आधुनिक, 28 निर्देशों वाला रिमोट-नियंत्रण यंत्र जिस से टीवी आपके इशारों पर चले.
- दो-तर्फ़ा डबल स्पीकर.
- पैनल-लॉक, जिसके प्रयोग से आप पूर्व-व्यवस्थित कंट्रोल्स को अनचाहे छेड़-छाड़ से सुरक्षित कर सकते हैं.

रोबोटेक्स

Texla®

naa/ND/TX-88

पंखों पे चली आएं...ताज़ी ठंडी हवाएं!

ओरिएन्ट फॅन्स

वक्त के साथ बदलने का नाम है शशि कपूर

'चार दीवारी' से अभिनय जीवन की शुरुआत करने वाले शशिकपूर वक्त के मिजाज के साथ बदलते रहे। यह बदलाव पहचान खोने जैसा नहीं रहा, बल्कि समय से हाथ मिलाकर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। व्यावसायिक फिल्मों की व्यस्तता से हटकर एक सर्मपित कलाकार की श्रेणी में आकर उन्होंने 'विजेता', 'कलयुग', 'जुनून', 'उत्सव' तथा '३६ चौरंगी लेन' जैसी समानांतर फिल्मों का निर्माण किया जो घाटे का सौदा साबित हुईं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे। आजकल वह 'अजूबा' जैसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म के निर्माण में लगे हुए हैं। चार दशक तक फिल्मों से जुड़े रहने वाले शशि कपूर की

अभिनय-यात्रा की दास्तान बता रहे हैं

—रवींद्र श्रीवास्तव :

लगभग ढाई दशक पूर्व शशि को बतौर नायक फिल्मों में लानेवाले निर्देशक किशन चोपड़ा थे या कनक मिश्र, इसमें विवाद है, लेकिन उनके किशोरावस्था के दोस्त रह चुके कनक मिश्र ने माटुंगा की सड़कों पर, जहां दोनों साथ रहा करते थे, जागिंग, डायटिंग तथा कसरत के सहारे मोटे शशि कपूर को स्लिम बनाकर सबसे पहले फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। पापाजी (स्व० पृथ्वीराज कपूर) के पृथ्वी थियेटर से फिल्मों में आये उनके इस बेटे को किशन चोपड़ा ने भी अनुबंधित कर लिया, लेकिन कनक मिश्र की फिल्म की जगह किशन चोपड़ा की 'चारदीवारी' पहले प्रदर्शित हुई, इसलिए शशि कपूंर की वही पहली फिल्म मान ली गयी।

कपूर खानदान की नियति है कि वे कभी भी अपनी पहली फिल्म से सुपर स्टार नहीं बन पाते, यही शशि कपूर के साथ भी हुआ। लगभग आधे दशक की सफल-असफल अभिनय यात्रा के बाद १९६५ में प्रदर्शित 'जब-जब फूल खिले' ने उन्हें स्टार बना दिया। फिर पुन: लगभग आधा दशक असफलता और गुमनामी के अंधेरे में भटकने के बाद 'चोर मचाये शोर' ने उन्हें सुपर स्टार बना दिया। भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में वह ऐसे पहले कलाकार हुए जो एक दिन में चार से छह फिल्मों की शूटिंग करते थे। एक ही स्टूडियो में उनकी चार-चार फिल्मों के सेट लगे होते थे—एक सेट पर एक शाट देकर कहानी व सिचुएशन के मुताबिक विग और कास्ट्यूम बदल कर दूसरे सेट पर, फिर तीसरे सेट पर और चौथे सेट पर शूटिंग कर पहले सेट पर शुरु के कास्ट्यूम में वापस आ जाते थे। मेकअप वह घर से करके चलते थे, सिर्फ अलग-अलग सेटों पर, अलग-अलग फिल्मों के कास्ट्यूम बदलने भर की जरूरत पड़ती थी। इस तरह उन्होंने पहली बार घंटों में शूटिंग करने की परंपरा डाली, जिसका फख्र आज भी उन्हें है। "इस तरह फिल्म निर्माता का नुकसान भी नहीं होता था और कलाकार के सामने 'डट्ेस के क्लैश' करने की समस्या भी नहीं होती थी। फिर हमारी हिंदी फिल्मों में डायलाग से लेकर सीन, सिचुएशंस तक सब कुछ लगभग समान ही होता है। कास्ट्यूम और विग बदल दीजिए, फिल्म अलग हो

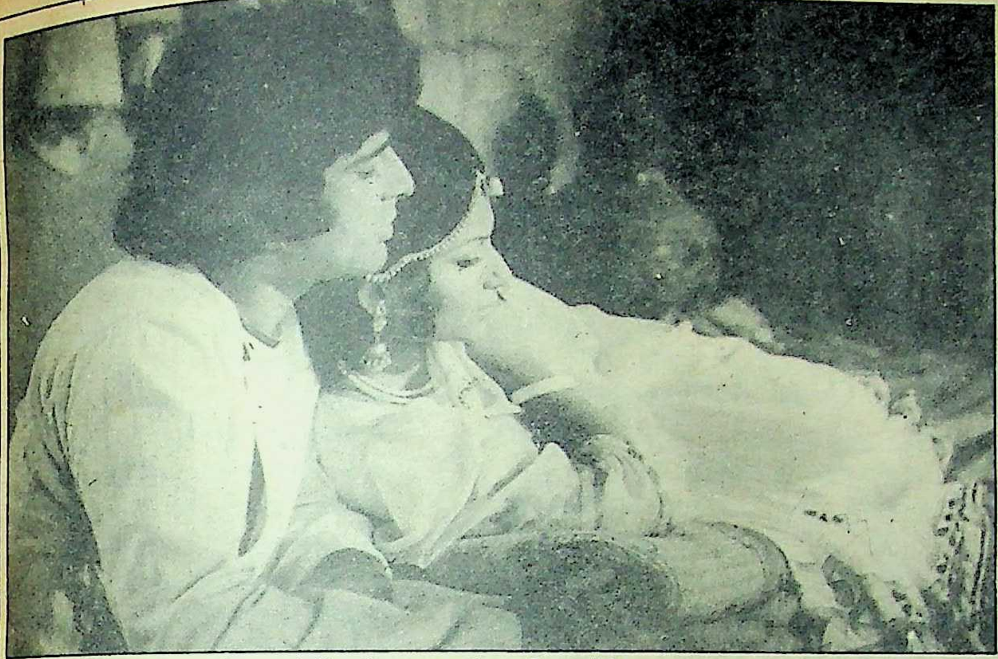

एक अलग अंदाज : 'पाप और पुण्य' में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर

समय को नमस्कार : एक फिल्म में शशि कपूर

गयी।" बड़े जोशो-खरोश से कहते हैं, शशि कपूर।

हर हाल में खुश : शशि हर बदलाव को बड़ी आसानी से लेते रहे, इसीलिए वह जिस मुकाम से शुरू हुए उस मुकाम पर आज भी यथावत हैं, जबकि उनके सामने तीन पीढ़ियां आयी-गयी हो गयीं। बदलाव को ग्रहण करने की उनकी यही प्रकृति थी कि जिस समय वह स्टारडम के शिखर पर थे और उनकी फिल्में अनमोल दामों में बिक रही थीं, वह उसी सहजता से यश चोपड़ा की दो फिल्मों ('कभी-कभी' और 'दीवार') में अपने से उस जूनियर कलाकार (अमिताभ बच्चन) के साथ सेकंड लीड करने के लिए तैयार हो गये, जो उनके साथ इस्माइल मर्चेंट की 'बांबे टाकीज' में लाश ढोनेवाले की भूमिका निभानेवाला महज एक्स्ट्रा कलाकार भर था। फिल्मों में काम न मिलने तथा बकौल निर्माता-निर्देशकों के 'सूरत तो देखी नहीं, चले आये फिल्मों में काम करने' जैसे जुमलों से आहत हो अमिताभ बच्चन निराशा के उन क्षणों में 'बाम्बे टाकीज' में एक दृश्य की एक्स्ट्रा-भूमिका निभाने कें लिए तैयार हो गये थे, लेकिन शशि कपूर ने उन्हें बुलाकार उनकी असफलता की कहानी सुनने के बाद उन्हें वह भूमिका न करने की सलाह देते हुए कहा था, "इतनी जल्दी हार मान गये बरखुदार! मुझे देखो, इतनी सारी फिल्मों में हीरो बनकर भी मैं जब 'आउट आफ मार्केट' हो गया, तो भी मैंने हार नहीं मानी! हिम्मत रखो, लड़ो-अंतिम क्षण तक लड़ो!"

अमिताभ को संघर्ष का यह मूल-तंत्र देने वाले शशि कपूर ने न केवल बड़ी सहजता से अमिताभ की सभी फिल्मों में सेकंड लीड वाली भूमिकाएं स्वीकार कर लीं, बल्कि अमिताभ बच्चन द्वारा इनकार कर दी गयी कोनराड रुक्स की फिल्म 'सिद्धार्थ' में भी उस सिमी गरेवाल के साथ काम करने के लिए तैयार हो गये जिसके साथ कोई भी कलाकार काम करने से मना कर देता था, इसीलिए सिम्मी अपनी तमाम अभिनय-खूबियों के बावजूद कभी सफल हीरोइन नहीं बन सकीं।

"मैं चाहता तो यश (यश चोपड़ा) और गुलशन राय को मना कर सकता था सेकंड लीड के लिए," अपने शशि कपूराना अंदाज में वह कहते हैं, "यह फिल्म मैंने तब की थी, जब फिल्म निर्माताओं की भीड़ मेरे चारों तरफ लगी रहती थी। लेकिन मेरी किसी को 'ना' कहने की आदत नहीं रही, फिर यार-दोस्तों को तो मैं सपने में भी मना नहीं कर सकता। अमित की 'जंजीर' जब मैंने देखी थी, तो मुझे लगा था कि इस लड़के में जो आग है, उसे भड़कने देना ही चाहिए। बस, मैंने यश की ही नहीं उन हर एक के आफर को मान लिया जो मुझे उसके साथ साइन करने आ रहे थे।" यह बात दूसरी है कि उसी अमिताभ ने शशि कपूर की फिल्म 'उत्सव' में उस समय काम करने से मना कर दिया था जब वह आर्थिक संकट में आकंठ डूबे थे और उन्हें अमिताभ की सिर्फ एक 'हां' की सख्त जरूरत थी।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति : शशि कपूर जितना अंग्रेजी फिल्मों के प्रति गंभीर रहे, उतना हिंदी फिल्मों के प्रति नहीं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्टार के रूप में तो ख्याति अर्जित करने में वह सफल रहे, लेकिन हिंदी फिल्मों- में कभी भी नंबर वन या टू' नहीं बन सके, नंबर थ्री से ही संतुष्ट रहे और इसकी कभी शिकायत नहीं की। "शिकायत किस बात की?" शशि कपूर का कहना था, "मैं सीरियस फिल्मों में काम करना चाहता था, लेकिन मुझे मिलते थे मसाला फिल्मों के घिसे-पिटे एक-से-एक रोल। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हर कुछ मंजूर करना पड़ेगा—तब तक जब तक आप कुछ खुद करनें की स्थिति में नहीं आ जाते।"

उनकी स्थिति जब सुदृढ़ हो गयी, तो उन्होंने सीरियस फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया। सीरियस फिल्मकारों की भीड़ में उन्होंने जब नजर दौड़ायी, तो सिर्फ उन्हें श्याम बेनेगल एकमात्र ऐसे निर्देशक लगे, जो अपने कथ्य के प्रति उतने ही ईमानदार थे, जितना अपने काम के प्रति। शशि खुद आगे बढ़े और उन्हें 'ब्लैंक चेक' दे दिया, "चाहे कितना भी खर्च हो, चाहे कितना भी घाटा हो, फिल्म अच्छी ही बनानी है।" और इस तरह कलात्मक फिल्मों के संसार में 'जुनून' का निर्माण हुआ, फिर 'कलयुग' का। 'कलयुग' के निर्माण के ही दौरान श्याम बेनेगल के कैमरामैन गोविंद निहलानी के 'विजेता' तथा 'कलयुग' के एक कलाकार गिरीश कर्नाड ने 'उत्सव' की कहानी उन्हें सुनायी। उन्हीं दिनों अभिनेत्री अपर्णा सेन, जो 'बाम्बे टाकीज' में उनकी नायिका रह चुकी थीं, को अपनी बंबई-यात्रा के दौरान '३६ चौरंगी लेन' की पटकथा सुनायी। शशि कपूर ने तमाम विरोधों के बावजूद उन तीनों को फिल्मों के निर्देशन का भार सौंप दिया, साथ ही अपना पर्स भी कि 'कुछ भी करो, लेकिन समझौता नहीं!'

"पहले मैं कामर्शियल फिल्मों में यों ही काम करता था, क्योंकि फिल्मों में ही रहना था," शशि कपूर बतलाते हैं, "लेकिन बाद में इसलिए करने लगा, क्योंकि इन फिल्मों के निर्माण के लिए धन की जरूरत थी और फायनेंसर व वितरक इसे (कला फिल्मों के निर्माण को) सिर्फ मेरा जुनून (पागलपन) मानते थे।" फलतः शुरू में पैसा लगाने के लिए वे आगे नहीं आते थे। इस तरह फिर शशि कपूर ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी कला-जुनूनी का एक नया अध्याय लिखा। 'जुनून' से लेकर 'उत्सव' तक हर फिल्म बाक्स आफिस पर फ्लाप हो कर्ज की राशि में इजाफा करती रही और शशि कपूर कामर्शियल फिल्मों में स्टूडियो के भीतर तीव्र प्रकाशवाली आर्कलाइटों तथा आउटडोर में सूरज की झुलसानेवाली गर्मी में दिन-रात काम कर कर्ज का बोझ हलका करते रहे। जो शशि कपूर कभी मुंहमांगी 'प्राइस' पर फिल्मों में काम करते रहे, उन्हें

साक्षात्कार/शशि कपूर

समानांतर या आर्ट फिल्म निरर्थक शब्द हैं

बम्बई का एकमात्र वातानुकूलित सेठ स्टूडियो, भारी भरकम काले पत्थरों की डरावनी, भयावनी, बदसूरत दीवारें, मोटे-मोटे सीखचों से युक्त दरवाजे, खिड़कियों वाली पुराने जमाने की कारागार। कालकोठरियों में से एक में डिम्पल कपाड़िया और दूसरे में सईद मिरजा बंद। बाहर बीच की खुली जगह में जुटी खासी भीड़। उस भीड़ में आधे हिंदुस्तानी और आधे सोवियत देश के टेक्नीशियन—डाइरेक्टर (जेन्नेदेजा वेसिलीव), उनके सहायक, कैमरामैन (सेरगीड), साउंड रिकार्डिस्ट इत्यादि। सेट का फर्श खास तौर पर झाड़ा बुहारा हुआ। कुरसियों पर विराजमान एक रूसी नागरिक अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ कर गिलास के आकार की पुड़िया बनाता है। अपनी सिगरेट जलाता है और राख को उस पुड़िया में इकट्ठी करता जाता है। सफाई की इस कदर आदत पड़ चुकी है उनको।

कालकोठरियों में धुआं और खिड़कियों से आने वाली प्रकाश की किरणों को दिखाने के लिए तसलों में जलते कोयले और उन पर छिड़का हुआ लोबान, धुओं के बादल उठाते सहायक मजदूर और उनके बीच से बाहर आते हुए कुरता पाजामा पहने शशि कपूर—हर किसी से हंसी-मजाक करते, लोगों का आलिंगन करते, पीठ थपथपाते, सहायकों को मीठे-मीठे आदेश देते हुए कुरसी पर आ बिराजते हैं। उन्होंने अपना शाट ले लिया है; अब उसी शाट को रूसी डाइरेक्टर वेसीलीव रूसी भाषा में लेने के लिए आगे बढ़ गये हैं। शशि कपूर से सेट पर ही हुई बेलाग बातचीत के अंश:

माया: मैं निर्देशक शशि कपूर से मिल रहा हूं या अभिनेता शशि कपूर से?

शशि: सिर्फ निर्देशक शशि कपूर से। अब डबल रोल वाला जमाना गया। एक जमाना था जब लोग डबल तो क्या तीन-तीन या उससे भी ज्यादा भूमिकाएं कर लिया करते थे।

माया: आप भी करते हैं?

शशि: मैं तो हमेशा से अलग ही रहता आया हूं। मेरी ऐसी पहचान बन गयी है।

माया: मगर आपकी इस 'अजूबा' फिल्म से उस पहचान को भीड़ में ला खड़ा करने की कोशिश नजर आ रही है।

शशि: बिलकुल नहीं। अब तक जो कुछ बनाया, वह औरों से तो अलग सिनेमा था ही, आपस में भी एक-दूसरे से बिलकुल अलग था। 'कलयुग', 'जुनून', 'विजेता' '३६ चौरंगीलेन', 'उत्सव'—इनमें आपस में कोई समानता नहीं।

माया: उनमें इतने भारी-भरकम सितारों का जमघट तो नहीं था।

शशि: जमघट तो वाकई नहीं था, मगर बड़े नामी कलाकार तो जरूर थे। तब तो मैं खुद भी स्टार था। रेखा भी मेरे साथ रहीं और शबाना आजमी भी रहीं।

माया: उनके बावजूद वे फिल्में समानांतर सिनेमा के अंतर्गत मानी गयीं।

शशि: समानांतर या आर्ट फिल्म निरर्थक शब्द हैं, जो उन लोगों ने गढ़ लिये हैं जिनकी फिल्में थियेटरों में नहीं पहुंचतीं। कोई फिल्म वितरक हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। मैंने उत्तम फिल्में बनायीं। यह भी वैसी ही फिल्म है, भले ही बाहर से देखने-सुनने में व्यवसायी लगती हो।

माया: यानी ये परिवर्तन आपने स्वीकार किये हैं?

शशि: परिवर्तन नहीं, एक प्रयोग कहिए।

माया: मुंशी प्रेमचन्द ने एक जगह लिखा है, "पक्षी कितना भी ऊंचा उड़े, उसे दाना चुगने के लिए धरती पर ही उतरना पड़ता है।"

शशि: वह महान लेखक थे। उन्होंने यह वाक्य जरूर मेरे लिए ही लिखा होगा। अलबत्ता इसमें इतना जरूर जोड़ूंगा कि दाना चोंच में लेने के बाद मैं फिर उसी ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऊंचा उड़ना मेरा शौक है। उस शौक से मेरा संबंध रंगमंच से रहा। पापाजी के साथ रंगमंच से ही मेरे अभिनय जीवन की शुरुआत हुई थी।

माया: उसी शौक में शादी भी हुई थी?

शशि: और वही शौक मुझे जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट के सम्पर्क में ले गया। उनके साथ मैंने पांच उत्तम श्रेणी की फिल्मों में काम किया—घरबार (हाउसहोल्डर), शेक्सपीयरवाला, बम्बईटाकी, हीट ऐंड डस्ट और द डिसीवर्स। ये आखिरी वाली फिल्म उसी लेखक की लिखी हुई थी जिसने भवानी जंक्शन लिखी थी। यह अंग्रेज मध्यप्रदेश में कई साल तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत में रहे थे। 'घरबार' को अमरीकी डाइरेक्टर ने बनाया था, मगर उसने संपूर्ण भारतीय घरेलू वातावरण, चरित्र-चित्रण वगैरह तैयार किये थे। बाद में जब अमरीकन निर्देशक कोनराड रुक्स को 'सिद्धार्थ' के लिए अभिनेता की जरूरत लगी, तो वह फिल्म भी उन्हीं सम्पर्कों की बदौलत मुझे मिली। उससे पहले कृष्ण चोपड़ा भी 'चार दीवारी' फिल्म बनाने के लिए मुझसे संपर्क कर चुके थे। वह फिल्म भी अपने आप में एक खूबसूरत फिल्म थी। उसमें मैंने भरपूर सहयोग दिया था, बिना किसी शर्त के।

माया: अच्छी और उत्तम फिल्मों के लंबे औ व्यापक संपर्क के बाद क्या अब परोक्ष रूप में यह अनुभूति हुई कि उतनी तमाम उत्तम फिल्में बना कर भी जीवन नैया भवसागर प नहीं कर सकती?

शशि: भवसागर पार करने के लिए अगर व्यवसायी बनना जरूरी होता, तो श्याम बेनेगल, सत्यजित राय जैसे निर्देशक तो कभी के विलीन हो गये होते। हां, यह बात जरूर कि मैं 'तमस' नहीं बना रहा हूं। गोविंद निहलानी उसे आर्ट फिल्म कहेंगे। मगर वह कुंठित दिमाग की उपज है। मैं उसे खूब जानता हूं। तीन फिल्मों में मेरे साथ काम क चुका है। पहले फोटोग्राफर, फिर निर्देशक की हैसियत से। मगर मुझे ताज्जुब होता है, इस फिल्म को उसने सरकारी विभाग से भी मान्यता दिलवायी है और टी०वी० अधिकारियों से भी पास कराया है। एन०एफ०डी०सी० और ब्लेज के मालिकों से भी शाबाशी कमायी है। किस कदर भारत विरोधी-हिंदू विरोधी और सिक्खपक्ष को खु करने वाली फिल्म बनायी है। ऐसी आत्म फिल्में इस देश में ही बन सकती हैं...

माया: आपकी 'जुनून' से भी इसी तरह की शिकायतें सुनने को मिली थीं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी पात्र मुस्लिम थे जबकि यह सर्वविदित है कि उस लड़ाई में उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी।

शशि: हां, वह शिकायत बहुत सही थी। रसकिन बांड ने 'फ्लाइट आफ द पिजंस' ना की कहानी लिखा था जिसमें एक पठान का

चरित्र था जिससे एक योरोपियन लड़की का प्रेम था। हमारी उस फिल्म का केंद्रबिंदु वह पात्र था, आजादी की लड़ाई तो पार्श्वभूमि में थी।

माया: क्या अब आप अभिनय से संन्यास लेंगे?

शशि: नहीं, मेरे आकारवाले लोगों की भी भूमिकाएं निकलती हैं, अमजद खां के लिए भी भूमिकाएं निकलती हैं। सत्यजित राय की टीवी सीरियल में भूमिका मिली ही थी।

माया: आपसे पहले राजकपूरजी निर्देशक बने, तो वह नयी उम्र के ही थे, पृथ्वीराजजी ने भी एक फिल्म का निर्देशन किया। रणधीर कपूर ने भी कम उम्र में ही निर्देशन शुरू किया था। शम्मी कपूर ने भी जल्दी ही ट्राई किया था, आपने बहुत देर लगायी?

शशि: निर्देशन तभी हो सकता है जब सोचने-समझने के लिए काफी समय हो। शम्मीजी ने भी तभी शुरू किया था जब हीरोशिप खतम होने लगी थी। राज साहब को निर्देशन का इस कदर शौक था कि वह दूसरे निर्माताओं की फिल्मों को स्वीकार करने से इनकार कर देते थे ताकि अपना काम करने के लिए काफी समय मिल सके।

> सोचा करता
> था कि भविष्य में जब
> लोगों की रुचि परिष्कृत हो जायेगी तब
> उन फिल्मों का जमाना आयेगा। ये चेक
> तब भुन जायेंगे। आयकर विभाग के
> लोग ताना मारा करते थे कि मैं ऐसी
> फिल्में बनाता ही इसलिए हूं कि
> नुकसान दिखा कर टैक्स बचाता रहूं। मैं
> भी उनके व्यंग्य का जवाब व्यंग्य में ही
> दिया करता था—चलो, आपका अंदाज
> ही सही। आयकर से इकट्ठा किया
> जानेवाला रुपया दूसरे कम आय वालों
> की मदद में खर्च किया जाता है। वही
> काम मैं अपने ढंग से कर रहा हूं।
> पापाजी का बेटा हूं। उन्होंने भी अपना
> पूरा पारिश्रमिक हमेशा पक्की रसीद
> देकर लिया और कभी आयकर विभाग
> को ठगा नहीं। थियेटर के बहाने वह
> क़ाफी बड़े दल को
> पालते रहे।

माया: पृथ्वी थियेटर का प्रयोग तो खूब सफल रहा।

शशि: उम्मीद से भी कहीं ज्यादा सफल रहा। मैंने विदेशों में यात्राएं कीं, तो इस तरह के छोटे-छोटे थियेटर देखे। पापाजी की स्मृति और थियेटरों के प्यार ने यह थियेटर यह सोचकर बनवा दिया था कि कभी-कभार शौकिया नाटक हो जाया करेंगे। बड़े नाटकों की रिहर्सल यहां हो जाया करेंगी। यह जगह भी लोगों के आने-जाने के खयाल से दूर थी। मौके की नहीं थी। इसलिए यह खयाल कभी आया ही नहीं कि यहां से कभी कोई आमदनी हो सकती है या यहां व्यवसायी नाटक भी हो सकते हैं। फिर संयोग ऐसा हो गया कि नाटक होने ही लग पड़े। पहले शनि-रवि से शुरुआत हुई, फिर रोज ही होने लगे। दो-दो शो भी होने लगे। कभी-कभी तीन भी हो जाते हैं। वहां का खर्चा आराम से निकल आता है। थियेटर बनवाने में जो खर्चा हुआ, वह अपने आप ही इनवेस्टमेंट (व्यवसाय में लगाया रुपया) बन गया। इसी नेक खयाली से अपनी फिल्मों में रुपया लगाना शुरू किया था। तब मैं उन फिल्मों को 'पोस्ट डेटेड चेक' कहा करता था (आगे आने वाली तारीखों का पेशगी चेक जो बाद में ही भुनाया जा सकता है)। सोचा करता था कि भविष्य में जब लोगों की रुचि परिष्कृत हो जायेगी तब उन फिल्मों का जमाना आयेगा। ये चेक तब भुन जायेंगे। आयकर विभाग के लोग ताना मारा करते थे कि मैं ऐसी फिल्में बनाता ही इसलिए हूं कि नुकसान दिखा कर टैक्स बचाता रहूं। मैं भी उनके व्यंग का जवाब व्यंग में ही दिया करता था—चलो, आपका अंदाज ही सही। आयकर से इकट्ठा किया जाने वाला रुपया दूसरे कम आय वालों की मदद में खर्च किया जाता है। वही काम मैं अपने ढंग से कर रहा हूं। पापाजी का बेटा हूं। उन्होंने भी अपना पूरा पारिश्रमिक हमेशा पक्की रसीद दे कर लिया और कभी आयकर विभाग को ठगा नहीं। थियेटर के बहाने वह काफी बड़े दल को पालते रहे।

माया: चलिये, उनके नाटकों ने कमा कर नहीं दिया। आपकी अब तक की फिल्मों ने भी कमा कर नहीं दिया मगर ये 'अजूबा' अगर चल गया, तो आयकर विभाग को कैसे टरकायेंगे?

शशि: तब टरकायेंगे क्यों? तब उस पैसे से भारत की जनता तो पलेगी हीं रूस की भी पलेगी और आयकर विभाग भी पलेगा।

—महेंद्र सरल

कर्ज पाटने के लिए डेली वेजेज पर छोटी-छोटी भूमिकाएं करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन हर बदलाव को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेने वाले शशि ने 'चढ़ते सूरज को प्रणाम करने वाले' फिल्म निर्माताओं के इस बदले तेवर को भी उसी सहजता से मंजूर कर लिया और कर्ज की एक-एक पाई चुकता कर दी। इसके लिए उन्हें उन दूरदर्शन सीरियलों में भी काम करना पड़ा, जिसकी (दूरदर्शन) कभी वह कड़ी आलोचना किया करते थे।

पृथ्वी थियेटर्स की शुरुआत: कला फिल्मों के प्रति रुझान के साथ-साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया—अपने स्वर्गीय पिता पृथ्वीराज कपूर की जिंदगी भर की आकांक्षा को साकार करने की। पृथ्वीराज कपूर मूलतः रंगमंच कलाकार थे और चाहते थे कि एक ऐसा पृथ्वी थियेटर्स बनाया जाये जहां मामूली खर्च कर शौकिया रंगकर्मी अपने नाटकों की मंच-प्रस्तुति कर सकें, लेकिन न तो उनके जीते जी और न ही उनकी मौत के बाद उनके दोनों करोड़पति पुत्रों (राज कपूर एवं शम्मी कपूर) ने उनके सपने को साकार करने की जरूरत महसूस की। शशि कपूर ने आर्थिक संकटों से जूझने के बावजूद, जानकी कुटीर में (जहां पृथ्वीराज कपूर ताजिंदगी रहे) पृथ्वी थियेटर्स का निर्माण कराया। "शुरू-शुरू में तो मैंने सोचा था कि बंबई के मुख्य शहरी इलाके में अपने नाटकों का प्रदर्शन करने वाले रंगकर्मी भला इस दूरदराज उपनगर के सूने क्षेत्र में क्यों आयेंगे। अगर वे आये भी, तो दर्शक नहीं मिलेंगे उन्हें।" शशि कपूर बतलाते हैं, "लेकिन हुआ एकदम उलटा! न केवल तीसों दिन यहां मंच प्रस्तुतियां और बुद्धिजीवियों का जमावड़ा होता है, बल्कि उनके हर शो फुल जाते हैं।"

सात वर्ष की उम्र में शशि कपूर को उनके बड़े भाई राज कपूर ने ८ एम०एम० का एक मूवी कैमरा थमाया था—'आवारा' में राज कपूर के बचपन की भूमिका करने के उपलक्ष्य में। और उस कैमरे से बालक शशि कपूर ने एक फिल्म बनायी थी, जिसके लेखक, निर्देशक सभी कुछ वही थे। और अब जिंदगी के साढ़े चार-पांच दशक की संधि-स्थल पर खड़े शशि कपूर निर्माता से निर्देशक भी बन गये हैं। हमेशा अमरीकी-ब्रितानी फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में काम करनेवाले शशि ने एक और बदलाव को सहजता से पुनः स्वीकार किया। वह सोवियत रूस के सहयोग से 'अजूबा' का निर्माण और निर्देशन कर रहे हैं जिसकी नायिका हैं रूसी अभिनेत्री और नायक हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें दो दशक पहले शशि ने जिंदगी के अंतिम क्षण तक संघर्ष की प्रेरणा दी थी। शशि कपूर 'अजूबा' में क्या करना चाहते हैं, न तो वह इसे बताना चाहते हैं और न ही अपने स्टार-हीरो के निर्देश पर प्रेस छायाकारों को 'अजूबा' के सेट पर घुसने की मंजूरी देते हैं। शायद यह भी उनके अजूबे शख्सीयत का एक अंग हो या इसे भी उन्होंने उसी सहजता से मंजूर कर लिया हो, जैसा पहले करते आये थे। ■

प्रोफेसर ए० रहमान

दोहरे चरित्र का संकट

यूरोप में विज्ञान के उदय और औद्योगिक क्रांति के बाद से यह आशा बलवती हुई थी कि विज्ञान व तकनीकी प्रगति गरीबी व असमानता का मसला हल करेगी। किंतु विकास के विविध चरणों के बावजूद विभिन्न वर्गों के बीच खाई बढ़ी है। इसके कई कारण बताये जाते हैं: मसलन मौजूदा समाज द्वारा विज्ञान का दुरुपयोग अथवा विज्ञान व तकनीक को धर्म और नैतिकता से अलग करना।

प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण संबंधी आधुनिक मानवीय समझदारी की एक विशेषता है—ज्ञान का विज्ञान, तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और धार्मिक इकाइयों में विभाजन। इनसे हरेक का पुनः विशेषीकृत क्षेत्रों में उपविभाजन होता है। दूसरे, ज्ञान के विकास के ऐतिहासिक क्रम में विचारों व दर्शनों का विभिन्न देशों व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग-अलग विकास हुआ है। तीसरे, ज्ञानोपलब्धि एक दोहरी प्रक्रिया है। इसके तहत नये को ग्रहण और पुराने को खारिज किया जाता है। किंतु अनेक पुराने विचार नये विचार के साथ-साथ अंतर्विरोधों के बावजूद चलते रहते हैं।

समाज में एक प्रकार के विचारों के प्रचलन का अर्थ यह नहीं कि अन्य विचारों का अस्तित्व नहीं होता है। मध्यकाल में धार्मिक गतिविधियां प्रभावी थीं, किंतु अन्य आर्थिक गतिविधियां भी विद्यमान थीं। मसलन उद्योग धंधों का विकास तत्कालीन सामाजिक विचारधारा को प्रभावित किये हुए था। भारतीय संस्कृति विभिन्न देशों की संस्कृतियों के आदान-प्रदान से विकसित हुई है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, सामाजिक-धार्मिक आंदोलन शामिल हैं। शताब्दियों तक भारत इतिहास के चौराहे पर रहा है। यह आदान-प्रदान धर्म (हिंदू, बौद्ध, इस्लाम व ईसाई), दर्शन, विज्ञान व तकनीक के माध्यम से हुआ। इस्लामी पुनर्जागरण का जन्म अब्बासी खलीफाओं द्वारा स्थापित दारुल-हिकमा (प्रज्ञा सदन) और औषधि, गणित तथा खगोल विज्ञान के संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से हुआ और जो भावी प्रगति का एक मूलाधार बना।

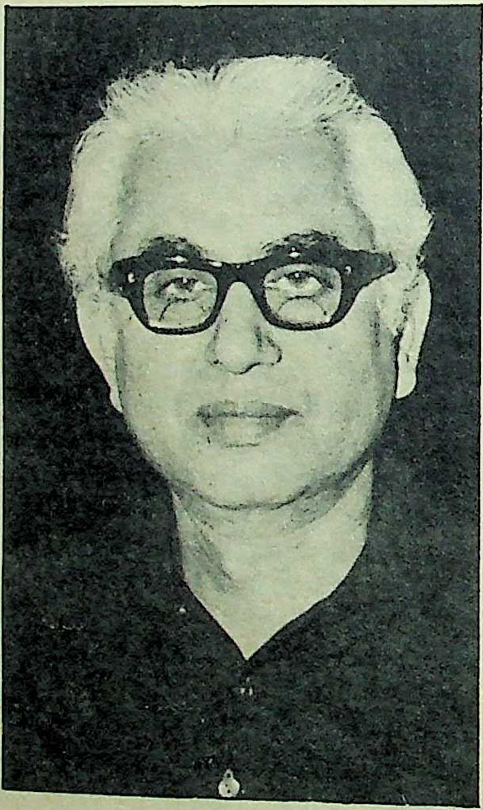

प्रोफेसर ए० रहमान: सीएसआईआर (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के पूर्व निदेशक, अनेक प्रख्यात राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों से संबद्ध, विविध चर्चित पुस्तकों के रचयिता और हिन्दी के मूर्धन्य महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज हैं।

दूसरा आदान-प्रदान १७वीं-१८वीं शताब्दी में यूरोपीय विज्ञान व तकनीक का हुआ—खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस प्रक्रिया में दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने यूरोप की नयी वेधशाला, खगोल विज्ञान के संयंत्रों—मसलन दूरबीन संबंधी जानकारियां हासिल कीं। तदनुसार उन्होंने पंचांग में सुधार करने और अधिक कारगर वेध-शालाएं बनाने का प्रयास किया। जय सिंह के कार्यों का दोहरा प्रभाव हुआ: विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि पुनः जागृत हुई। खासकर निरीक्षण और प्रयोग के क्षेत्र में। यह प्रवृत्ति भारत में ह्रासोन्मुखी थी। इसके अलावा विज्ञान और उसकी उपलब्धियों का महत्व लोगों को जताने के लिए उन्होंने वेधशालाओं के निर्माण के अलावा एक नये नगर जयपुर की योजना बनायी।

यूरोपीय विद्वान विज्ञान और तकनीक को एक यूरोपीय देन और इसे यूरोप द्वारा भारत को दी गयी एक भेंट मानते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि अविकसित देशों का वैज्ञानिक-तकनीकी विकास यूरोप-अमरीका के नेतृत्व में ही संभव है और इसी से उनका सामाजिक-सांस्कृतिक रूपांतरण होगा। उन्होंने इस तथ्य को पूर्णतया अनदेखा किया कि भारत, चीन, पश्चिम व मध्य एशिया में विज्ञान व तकनीक की एक सुदृढ़ परंपरा थी।

भारत में विज्ञान के पहले तकनीक का प्रवेश हुआ। इसका साधनों के दोहन व देश में विदेशी सामानों की बिक्री के एक औजार के रूप में प्रवेश हुआ। विदेशी वस्तुओं व भारतीय वस्तुओं का सीधा संघर्ष हुआ। कच्चे माल की मांग की पूर्ति व विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े परिवर्तन किये गये, जिससे भारतीय जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा।

बाद में जब आयातित तकनीक के बलबूते उद्योग की स्थापना हुई, तो एक दोहरी उत्पादन प्रणाली का उदय हुआ। यह दोहरापन ऊपर से आरोपित तथा विभिन्न धर्मावलंबी विदेशियों से संबंधित था। फलस्वरूप दो प्रणालियां 'भारतीय' व 'विदेशी' नाम से जानी जाने लगीं। पहली स्वाधीनता आंदोलन व गांधीवादी विचारधारा के तहत राष्ट्रीयतावाद से जुड़कर उत्पादन प्रणालियों के एक संभावित विकल्प के रूप में उजागर हुई। दूसरी को संगठित उद्योग के मानवविरोधी शोषणकारी चरित्र को समाप्त करने के लिए लाया गया। यह द्वैतवाद देश की औद्योगिक योजना में आज भी जारी है।

पारंपरिक क्षेत्र को औद्योगिक प्रगति में सफलता न मिलने का कारण है—हमारी शिक्षा

प्रणाली। तकनीकी शिक्षा का ढांचा ही ऐसा बनाया गया जो आयातित तकनीक पर आधारित इकाइयों की जरूरतों का पूरक हो। इसका उद्भव और विकास पारंपरिक घरेलू और लघु उद्योग धंधों से नहीं हुआ। आयातित तकनीक वाले उद्योग सरकारी सहयोग पर आधारित होने के कारण नौकरशाही शिकंजे से ग्रस्त हो गये। इसलिए यह सामाजिक रूपांतरण की भूमिका नहीं निभा सका।

यूरोप के विपरीत भारत के दस्तकारों और कारीगरों को विज्ञान तथा तकनीक का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। नतीजतन वे आधुनिक प्रगति से अलग-थलग रहकर पारंपरिक ज्ञान से चिपके रहे और उनकी हालत बदतर होती गयी।

मौजूदा उत्पादन की इस दोहरी प्रणाली में एक देशज थी और दूसरी बाहर से आरोपित। दूसरी प्रणाली का तकनीक के लगातार आयात से वर्चस्व कायम हो गया। इस दोहरे चरित्र ने सामाजिक विभाजन की बुनियाद डाली। कारण ये समाज के दो विभिन्न वर्गों का हित साधन कर रही थीं। एक संपन्न वर्ग का दूसरा निर्धन वर्ग का।

भारत में अपनायी गयी विज्ञान व तकनीकी नीति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ायी है और इस दोहरे चरित्र को सुदृढ़ किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर ज्ञान प्राप्त छात्र यूरोपीय-अमरीकी विज्ञान, तकनीक और उनके मौजूदा सामाजिक दर्शन और अन्य मसलों से तो परिचित होते हैं, किंतु भारतीय वैज्ञानिक व तकनीकी परंपरा की दृष्टि से कोरे होते हैं। अंततः वे या तो उन देशों की संस्कृतियों से तारतम्य जोड़ते हैं अथवा वहां जाकर बस जाते हैं।

उभरता भारतीय उद्योग आयातित तकनीक की बुनियाद पर खड़ा है। आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले तकनीक का आयात उद्योग लगाने के लिए किया गया, फिर निर्यात संवर्धन के लिए, फिर पुरानी पड़ गयी तकनीक को बदलने के लिए, पुनः प्रतिद्वंद्विता लाने के लिए और अब अत्याधुनिक तकनीक के नाम पर। इसके अलावा अहम सवाल है कि आयातित तकनीक समाज के किस वर्ग के लाभ के लिए है?

बहुसंख्यक तकनीक, खासकर निजी क्षेत्र में, समाज के धनी वर्ग की जरूरतों और मांगों को पूरा करने और उपभोक्तावाद के संवर्धन के लिए है। यह अखबारों व टीवी के विज्ञापनों से उजागर है। माडलों की बोली, व्यवहार, पोशाक अमरीकी उपभोक्ता संस्कृति की भोंडी नकल लगती है। और यह सब तब हो रहा है जब करोड़ों लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आंकड़ों के अनुसार आधी आबादी को पौष्टिक आहार मयस्सर नहीं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी दो प्रणालियां कायम हैं। एक, देशी अर्थात पारंपरिक। दूसरी अंग्रजों द्वारा प्रचलित आधुनिक। इन दोनों की माध्यम भाषा भी अलग है। पारंपरिक शिक्षा आधुनिक वैज्ञानिक बोध के स्थान पर मध्यकालीन ज्ञान से संपृक्त हो गयी। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा अपनी वैज्ञानिक परंपरा और संस्कृति से बेखबर हो छात्रों को यूरोपीय सिद्धांत व विचारधारा के माध्यम से अपने अतीत की व्याख्या प्रस्तुत करती है। इस प्रकार शिक्षा में भी एक दोहरे चरित्र का निर्माण हुआ।

इस द्वैतवाद का एक रूप सामाजिक था, जिसके उदय का कारण है जनता के विभिन्न वर्गों में प्रगति के लाभों का असमान वितरण। जिन्हें लाभ नहीं हुआ, वे कुछ पाने के लिए भटकने लगे। मंसलन अतीत के दर्शन और मूल्यों की ओर वापसी। इसी प्रक्रिया में प्रगति के अगले चरण ने अमरीका व यूरोप में अतीत की ओर लोगों को झांकने के लिए विवश किया।

> शिक्षा के क्षेत्र में भी दो प्रणालियां कायम हैं। एक, देशी अर्थात पारंपरिक। दूसरी अंग्रेज़ों द्वारा प्रचलित आधुनिक। इन दोनों की माध्यम भाषा भी अलग है। पारंपरिक शिक्षा आधुनिक वैज्ञानिक बोध के स्थान पर मध्यकालीन ज्ञान से संपृक्त हो गयी। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा अपनी वैज्ञानिक परंपरा और संस्कृति से बेखबर हो छात्रों को यूरोपीय सिद्धांत व विचारधारा के माध्यम से अपने अतीत की व्याख्या प्रस्तुत करती है। इस प्रकार शिक्षा में भी एक दोहरे चरित्र का निर्माण हुआ।

इस दौर में भारत के धार्मिक अभियानों को प्रभावकारी विज्ञापनों व व्यावसायिक दक्षता के फलस्वरूप पश्चिमी समाज की उर्वर भूमि और व्यापक अनुयायी प्राप्त हुए। इन 'गुरुओं' ने ध्यान, मंत्र, सामुदायिक जीवन, मुक्त सेक्स, गीत-नृत्य का धुआंधार प्रचार तनाव से मुक्ति और सामाजिक समस्याओं के हल के नाम पर किया।

यूरोप, अमरीका में इस संगठित अभियान की सफलता ने भारत में भी ऐसे कर्मकांडों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया—खासकर प्रगति से लाभान्वित न होने वाले लोगों का। इस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीतिक दुस्साहस ने विभिन्न नकाब चढ़ाकर सिर उठाना शुरू किया—मसलन कठमुल्लावाद। नतीजतन यह एक प्रमुख सामाजिक मसला बन गया। यदि वैज्ञानिकों ने अपने को समाज से अलग-थलग न किया होता, तो कठमुल्लावाद इतनी तेजी और गहराई से देश में न उभरता।

भारत विभिन्न धर्मों-भाषाओं का देश है। इसे एकता के सूत्र में पिरोने के लिए समय-समय पर धर्म, भाषा और संस्कृति का सहारा लिया गया। राष्ट्रीय एकता लाने के लिए गांधीजी ने जहां सामाजिक-राजनीतिक सुधारों का प्रश्रय लिया, वहीं नेहरू ने राष्ट्रवाद व विज्ञान का।

कठोर वर्णाश्रम धर्म के कारण पहले ज्ञानार्जन पर विशेष जातियों का एकाधिकार था तथा 'अस्पृश्यों' के लिए यह अमान्य था। गांधीजी ने इस श्रेणी विभाजन व खासकर अस्पृश्यता के खिलाफ जेहाद बोला। इससे भारतीय विचारधारा, दर्शन व परंपरा में एक नयी संस्कृति का सूत्रपात हुआ। नेहरू के दर्शन ने पीड़ितों-वंचितों के लिए शिक्षा, नौकरी व विकास की विशेष सुविधाएं जुटाकर एक अन्य महत्वपूर्ण मुहिम चलायी। इस दौर में विज्ञान व संस्कृति का भारतीय मसलों के संदर्भ में तालमेल, पुराने और नये का संगम व समायोजन द्वारा अनेकता में एकता के प्रयास सराहनीय रहे हैं। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद की घटनाओं से इस मुद्दे पर गंभीर पुनरावलोकन आवश्यक हो गया है।

भारत का आधुनिक विज्ञान में प्रवेश ऐसे समय में हुआ है, जबकि विज्ञान की नूतन दृष्टि और मूल्य प्रदान करने की शक्ति हाशिये पर डाल दी गयी है। आज भारतीय समाज बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मूल्यों की दृष्टि से पूर्णतया विभाजित है। एक छोटे तबके के सामने यूरोपीय-अमरीकी समाज और उसके उपभोक्तावाद, कचरा संस्कृति व मात्र संपन्न वर्गों के लाभ की तर्ज पर भविष्य की छवि है। प्रगति से वंचित करोड़ों लोग अतीतजीवी बन कर पुरातन ज्ञान और पुरानी तकनीक को अपनाने को मजबूर हैं।

इस संकट को विज्ञान की भूमिका में ऐसा रूपांतरण करके दूर किया जा सकता है, जिससे लोगों का नजरिया बदल सके, उन्हें नये समसामयिक मूल्यों से लैस किया जा सके। ऐसा न होने और विज्ञान को आज जैसा अलग-थलग करने से वह कट्टरवाद व मध्यकालीन विचारधारा की ताकतों एवं फौजी तानाशाही की हुकूमतों के हाथों बंधक हो जायेगा जैसा चंद पड़ोसी देशों में हुआ है। ■

दौड़ जूतों के लिए

देश में दौड़ की एक नयी लहर देखने में आ रही है। लोग दौड़ने लगे हैं—अपने शारीरिक व्यक्तित्व को निखारने, बीमारी को दूर रखने या पुरस्कार जीतने के लिए? जो रोज नहीं दौड़ पाते, वे देश के लिए ही दौड़ लेते हैं— कभी-कभी जीवन में एक-दो बार। अब इस दौड़ में कुछ कंपनियां भी शामिल होने के लिए व्याकुल हैं। माहौल माकूल है, तो कुछ अपनी भी तरक्की क्यों न की जाये? इसलिए क्यों न दौड़ लगाने के लिए नामी और सुंदर स्पोर्ट्स जूते तैयार करके दौड़ने वालों का मन लुभाया जाये? दौड़ लगाने वालों में नया जोश तो पैदा होगा ही, साथ ही इन कंपनियों की आय-रेखा भी ऊपर की ओर भागती नजर नजर आयेगी। हर स्थिति को अपने मुनाफे के माफिक मोड़ने में उद्योगपतियों का कोई जवाब नहीं!

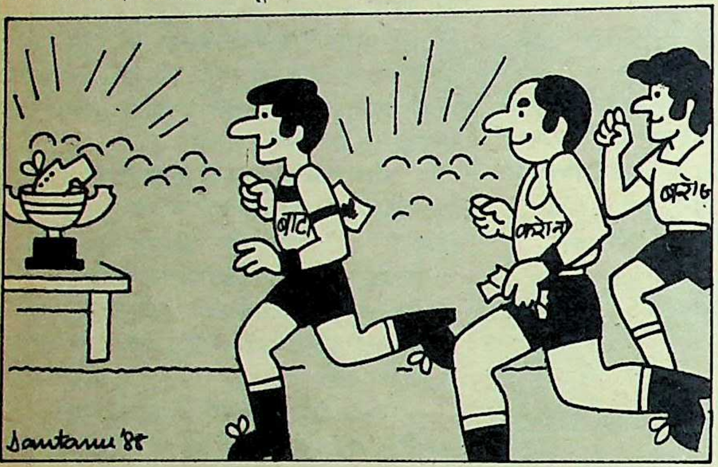

बाटा कंपनी काफी तेजी से इस दिशा में गतिशील है और जल्द ही विश्व-प्रसिद्ध 'अडीडास' स्पोर्ट्स जूतों का उत्पादन शुरू करने वाली है। उत्पादन के लिए सरकारी स्वीकृति शीघ्र मिलने की आशा है। अड़चन केवल अब इतनी ही रह गयी है कि विदेशी विनियोग बोर्ड इस बात पर अड़ा है कि बाटा को ऐसे जूतों का ७५ प्रतिशत निर्यात करना आवश्यक होगा, जबकि कंपनी ५० प्रतिशत ही निर्यात के लिए रजामंद है। एक दूसरी कंपनी, केरोना-साहू, ने भी पश्चिम जर्मनी की फर्म-पूमा-से ऐसे जूतों के उत्पादन के लिए गठबंधन किया है, परंतु व्यवधान यहां भी निर्यात संबंधी सरकारी शर्त का ही है। केरोना साहू इस बात पर अड़ी है कि वह ऐसे जूतों का केवल २५ प्रतिशत ही निर्यात करेगी। अन्य और कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। इनमें दवा बनाने वाली एक कंपनी बेरोज वेलकम भी है।

इन सभी में बाटा कंपनी की योजना ही सबसे अधिक व्यापक है। विश्व के अन्य भागों में अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स जूते बनाने के लिए बाटा को पहले से ही प्रसिद्धि हासिल है। परंतु, भारतीय जूता बाजार में मौजूदा उत्साहवर्द्धक स्थिति को देखते हुए बाटा कंपनी विदेशों में अपनी औद्योगिक गतिविधियों का एक अच्छा-खासा हिस्सा भारत में लाना चाह रही है। बाहरी देशों की तुलना में भारत में उत्पादन लागत भी कम है और यह बाटा कंपनी के लिए एक विशेष आकर्षण है। यह स्वाभाविक है कि भारत में कम खर्च पर बने स्पोर्ट्स जूतों को निर्यात करके बाटा कंपनी मुनाफे की दौड़ में औरों को पीछे छोड़ जायेगी। यही व्यापारिक सूझ-बूझ और दूरदृष्टि संभवतः बाटा की अब तक की कामयाबी का राज रहा है।

कर्ज का फंदा

भारत सरकार आर्थिक विकास चाहे कितना ही ढिंढोरा क्यों न पीटे, हकीकत यह है कि देश पर दिनोदिन कर्ज-भार बढ़ता ही जा रहा है—न केवल आंतरिक कर्ज का, बल्कि बाहरी कर्ज का भी। आंतरिक कर्ज कितना है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन बाहरी ऋण के बारे में सरकारी आंकड़े भरमाने वाले जरूर हैं।

सरकारी अनुमान के अनुसार मार्च १९८८ के अंत तक आंतरिक कर्ज की राशि एक नयी ऊंचाई को छू लेगी, यानी यह रकम उस समय तक ९८,१५० करोड़ रुपयों तक पहुंच जायेगी। लगता है अपने ही देश के लोगों से कर्ज लेने के मामले में हमारी सरकार ने गांव के दरिद्र भूमिहीन किसानों या शहर के गरीब लोगों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। अधिक नहीं, केवल दस साल पहले देश का आंतरिक कर्ज केवल १९,६३० करोड़ था, यानी आज के कर्ज का मात्र १/५ भाग और १९७० में कर्ज की कुल रकम केवल उतनी ही थी, जितनी भारत सरकार आज आंतरिक कर्ज पर अपने ही देश के लोगों को ब्याज के रूप में अदा कर रही है।

लेकिन देश पर बाहरी कर्ज वास्तव में कितना है? सरकार का कहना है कि यह केवल २३,००० करोड़ ही रुपए है। बाहरी कर्ज की राशि भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं, जितनी आंतरिक कर्ज की। स्वाभाविक ही है ऐसा होना, क्योंकि अपने देशवासियों से कर्ज लेना ज्यादा आसान होता है, बजाय बाहर के लोगों से, जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन देश पर वास्तव में बाहरी ऋण कितना है, इस संबंध में विश्व बैंक के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। उनके अनुसार इस समय देश पर बाहरी कर्ज का बोझ २३,००० करोड़ रुपए नहीं, बल्कि ६०,००० करोड़ रुपए है। हमारी सरकार और विश्व बैंक के आंकड़ों में यह अंतर्विरोध क्यों? सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार उसके आंकड़ों में निजी खातों में ली गयी कर्ज की राशि का समावेश नहीं किया गया है, उनमें केवल ऐसे ही कर्ज की रकम शामिल की गयी है जो सरकार ने स्वयं ले रखी है। यह तर्क समझ के परे है। कर्ज, चाहे वह कैसा भी हो कर्ज ही होता है, क्योंकि संपूर्ण विदेशी मुद्रा केवल सरकार द्वारा ही नियमित और नियंत्रित की जाती है और जो भी विदेशी मुद्रा उधार ली गयी है चाहे वह निजी खाते से ली गयी हो या सरकारी खाते से, अदायगी की अंतिम जिम्मेदारी भारत सरकार पर ही है। इसके अलावा, एक और तथ्य सरकार की आंकड़ों की सचाई को संदिग्ध बनाता है। जब विदेशी कर्ज लिया गया था, उस समय रुपयों में डालर की कीमत कम थी, परंतु आज डालर की कीमत कहीं अधिक है। अर्थात, भारत सरकार को कर्ज या ब्याज की अदायगी अब अधिक रकम में करनी पड़ेगी। सरकारी आंकड़ा बनाते समय क्या विदेशी कर्ज की इस बढ़ोतरी का भी ध्यान रखा गया था? कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि आंकड़ा तैयार करने की कला में भारत सरकार की बराबरी शायद ही अन्य कोई कर सके।

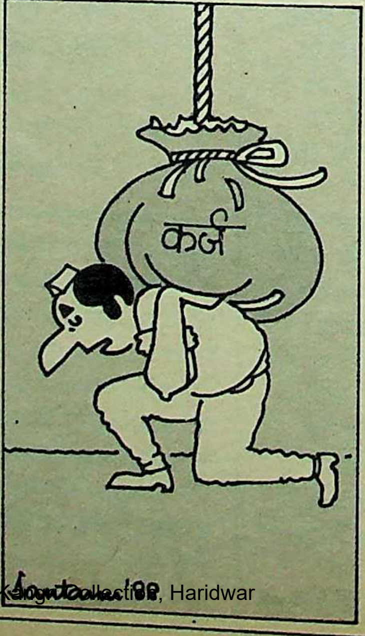

औद्योगिक विकास या ठहराव?

आंकड़ों की चर्चा जब हो रही है, तो एक नजर उस सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण पर भी डाली जाये, जो वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस साल संसद में पेश किया था। सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि इस वर्ष देश की वार्षिक औद्योगिक वृद्धि लगभग १० प्रतिशत तक होगी। कितना सच है यह दावा, जबकि इस्पात व कपड़ा जैसे बड़े धंधों की उत्पादन-वृद्धि दर काफी धीमी रही है? इसके अलावा, जब देश में बिजली का उत्पादन ही निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे झूल कर रह गया

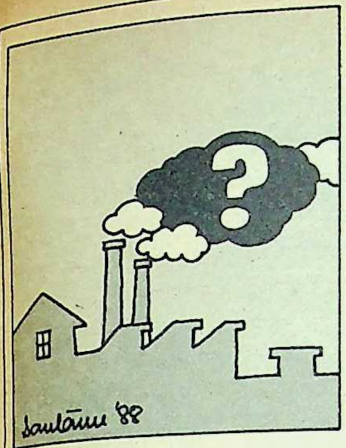

है, तो फिर औद्योगिक उत्पादन, यथेष्ट ऊर्जा का अभाव होते हुए भी, अपने लक्ष्य को कैसे पार कर गया? क्या हमें बिजलीरहित उद्योगों के माध्यम से भी राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने की महारत हासिल है? और, यदि हमारे उद्योग लक्ष्य से अधिक उत्पादक हो चले हैं, जैसा सरकारी आंकड़े कहते हैं, तो देश के शेयर बाजारों में जोश के बजाय संशय और सन्नाटे का नजारा क्यों दिखायी पड़ रहा है?

राजस्थान अब आगे है

बात चौंकानेवाली जरूर है, लेकिन है सच—रेगिस्तानी और रेतीली धरती पर तरक्की के नये आयाम! जबकि पूरा देश १९८० से लेकर अब तक ५ प्रतिशत विकास-दर पर ही अटक कर रह गया, राजस्थान ने इसी दौरान ७.८ प्रतिशत वार्षिक प्रगति हासिल कर अन्य राज्यों को पछाड़ दिया है। अन्य चुस्त राज्यों में दूसरा स्थान तमिलनाडु का है (विकास-दर ६.९ प्रतिशत), तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश (विकास-दर ६ प्रतिशत) और सर्वाधिक अकर्मण्य राज्य सिद्ध हुआ है गुजरात, जिसकी विकास-दर मुश्किल से १.१ प्रतिशत ही रही। अन्य सुस्त राज्यों में दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा (१.२ प्रतिशत) और तीसरा स्थान केरल का (१.४ प्रतिशत)।

गुजरात की दुर्दशा का क्या कारण हो सकता है, जबकि सरकारी विज्ञापनों पर निरंतर पैसे खर्च करके वह 'सर्वाधिक प्रगतिशील और क्रियाशील राज्य' होने का निःसंकोच दावा करती रही है? वास्तव में, विसंगति गुजरात के साथ यह हुई कि राज्य सरकार ने उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया और कृषि के प्रति सौतेला व्यवहार अपनाया। नतीजा यह हुआ कि वहां पर कृषि विकास-दर घटकर केवल—३ प्रतिशत रह गयी और इस तरह गुजरात करीब-करीब महाराष्ट्र के करीब जा लगा, जहां कृषि विकास-दर शून्य रही। आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी भी इन दोनों राज्यों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ है कि विकास की दौड़ में ये कितने पीछे छूट गये हैं। फिर भी, उनके सरकारी विज्ञापन ढोल बजाते जा रहे हैं—सर्वव्यापी विकास का, अभूतपूर्व आर्थिक-प्रगति का।

यदि हम विश्व की ओर निगाह दौड़ाएं, तो कृषि के प्रति लापरवाही का नतीजा क्या होता है, उसका जीता-जागता मिसाल रूस है। वहां पर भी १९१७ की क्रांति के बाद, साम्यवादी सरकार कृषि को नजरअंदाज कर उद्योगों के विकास पर लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक विकास की दर में अब वह केवल जापान से ही नहीं पिछड़ गया है, बल्कि आज भी पेट भरने के लिए उसे अमरीका से अन्न-आयात के लिए हाथ पसारना पड़ रहा है। अब जाकर कहीं रूस ने यह अहसास किया है कि कृषि का भी विकास तेजी से किया जाना चाहिए। इसका श्रेय गोर्बाचेव को जाता है जो रूस की आर्थिक स्थिति को एक नयी दिशा देने के लिए व्याकुल हैं। हमारा देश भी पिछले कई वर्षों से कृषि के मामले में रूस के ही पदचिह्नों पर चलता रहा है, परंतु पिछले बजट में कृषि की ओर दिया गया विशेष ध्यान इस ओर संकेत करता है कि शायद भारत सरकार को भी यथार्थ-ज्ञान हो रहा है। और हो भी क्यों न—रूस जो जाग गया है! ■

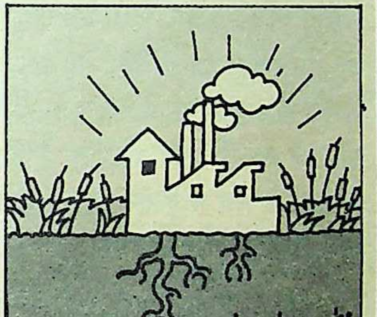

कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब
चुटकी पान मसाला खाईए जनाब
सौंफ इलायची छुआरे वाला
चुटकी
पान मसाला
Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"
Chutki
CHUTKI
चुटकी
ਚੁਟਕੀ
சுட்க்கி
ಚುಟಕಿ
ચુટકી
చుట్కీ
के.के. कार्यालय का उत्कृष्ट उत्पादन

'कानसेन' से 'तानसेन' की ओर : कर्ण सिंह

डा० कर्ण सिंह

'महाराजा' नहीं, बुद्धिजीवी

जम्मू-कश्मीर उन पांच बड़ी रियासतों में एक थी, जिसके शासक को २१ तोपों की सलामी दी जाती थी। डा० कर्ण सिंह इसी रियासत के वंशज हैं। लेकिन युवा कर्ण सिंह ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि सामंतशाही के दिन लद चुके हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का प्रयास करना शुरू कर दिया जिससे वह अपनी पहचान के लिए अपनी विरासत के मोहताज न रहें। इसीलिए आज उनको नाज है कि वह एक भूतपूर्व राजा के बजाय एक बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सर्वाधिक युवा मंत्री के रूप में प्रवेश किया था और दस साल तक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने एक कुशल प्रशासक और कूटनीतिनिपुण राजनेता की छवि बनायी। अब वह सत्ता के केंद्र में नहीं हैं , धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में कार्यरत हैं। कर्णसिंह के बहुविध व्यक्तित्व का रंजना कक्कड़ द्वारा आकलन :

डा० कर्ण सिंह—जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व महाराजा। लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं कि उनको कोई महाराजा कह कर बुलाये। उन्हें डा० कर्ण सिंह कहलाना ज्यादा पसंद है—पहले भी और अब भी। डा० कर्ण सिंह उन गिने-चुने भूतपूर्व महाराजाओं में हैं, जिनकी गिनती बुद्धिजीवियों में होती है। स्नेहशील और हंसमुख डा० कर्ण सिंह को आप हमेशा पारंपरिक कश्मीरी टोपी में पायेंगे। उन्हें अपने शाही खानदान पर गर्व है, लेकिन इसका कोई अहंकार नहीं। हां, उन्हें अपनी डाक्टरेट की उपाधि पर अवश्य नाज है। वह कहते हैं, "मैं ज्यादा दिनों तक महाराजा नहीं रहा। यदि आपका जन्म भी महाराजा के यहां होता, तो स्वाभाविक रूप से आप भी महाराज हो जाते। लेकिन डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। बेशक मैं अपनी विरासत पर गर्व करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कर्म को महत्व देता हूं, साथ ही मैंने खुद क्या प्राप्त किया है, उसको भी।"

यह आसान काम नहीं था। खासतौर पर कर्ण सिंह के लिए जो काफी इंतजार के बाद जन्मे थे। डा० कर्ण सिंह के पिता सर हरि सिंह ने तीन शादियां की थीं और मार्च १९३१ में कर्ण सिंह के जन्म से पहले वह निस्संतान थे। जब भूमध्य सागर पर स्थित फ्रांस के शहर केंज के होटल मार्टिनेज में कर्ण सिंह का जन्म हुआ, तो केवल राज परिवार में ही नहीं, दूर-दराज कश्मीर में उनकी रियाया हर्षोल्लास से भर गयी थी। लाडली संतान और वह भी इतने बड़े राज परिवार की—जाहिर है विधिवत पढ़ाई और डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में जुटना आसान नहीं था। लेकिन बकौल डा० कर्ण सिंह, उनकी इस उपलब्धि में दो चीजें मददगार साबित हुईं, "एक मेरी मां जो एक गरीब देहाती परिवार में जन्मी थीं। उनका यह पवित्र वाक्य मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता था कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। दूसरे, मेरे पिता ने एक समझदारी भरा फैसला लिया और मुझे दरबारी माहौल से दूर रखा।"

केवल तीन वर्ष की उम्र से ही कर्ण सिंह को न केवल दरबारी माहौल से दूर रखा गया, बल्कि उन्हें उनकी मां से भी अलग कर दिया गया। एक अलग जगह उनकी देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी आयरिश ननों को सौंप दी गयी। कर्ण सिंह बताते हैं, "मैं दिन में केवल एक घंटे मां के पास रह सकता था और पिता से हफ्ते में तीन बार ही मिल सकता था। यह कोई आदर्श पारिवारिक माहौल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका कारण था मेरे बेमेल माता-पिता।"

कुछ सालों बाद उन्हें दून स्कूल में भरती कर दिया गया। छुट्टियों में कर्ण सिंह को सार्वजनिक जीवन के लिए दीक्षित किया जाता, जोकि एक युवराज के लिए जरूरी था। उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण ११ साल की उम्र में दिया, जिसने अंततः हर वर्ष दुहराये जाने वाले आयोजन का रूप ले लिया। लेकिन छुट्टियों का मतलब पिकनिक और परिवार से मिलना-जुलना भी था। "१९४३ से १९४६ के बीच ही मुझे सामान्य पारिवारिक माहौल प्राप्त हुआ। हम मीनू (भोजन सूची) और बैठने की व्यवस्था की योजना तैयार करने में घंटों खर्च करते थे।"

परिवर्तन का अहसास : यद्यपि उस समय श्री सिंह को दून स्कूल का रहन-सहन नहीं भाया था। खुरदरे नीले कंबलों और गमगीन नीली चादरों से उन्हें सख्त नफरत थी। लेकिन आज वह इस बात को सराहते हैं कि उनकी शिक्षा-दीक्षा 'शाही' स्कूल में नहीं हुई। दून स्कूल ने उन्हें नयी दुनिया के अनुरूप ढलने में मदद की और शायद इसीलिए शाही अहं को त्याग कर वह डा० कर्ण सिंह कहलवाना पसंद करते हैं। वह कहते हैं, "मैंने दून में ही यह महसूस किया कि छोटी सामंती दुनिया, जिसमें हम रहते हैं, अब बदलने वाली है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में महान ऐतिहासिक शक्तियां काम कर रही हैं और यह एक छोटा-मोटा नहीं, बल्कि इतिहास के महान आंदोलनों में से एक है।"

भारत की पांच सौ से भी ज्यादा रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत के इकलौते वारिस कर्ण सिंह

एक दूसरे के पूरक: डा० कर्ण सिंह अपनी पत्नी आशा के साथ

> यदि आपका जन्म भी महाराजा के यहां होता, तो स्वाभाविक रूप से आप भी महाराज हो जाते। लेकिन डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। बेशक मैं अपनी विरासत पर गर्व करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कर्म को महत्व देता हूं, साथ ही मैंने खुद क्या प्राप्त किया है, उसको भी।

की जिन्दगी सामंती युग से लोकतंत्र तक फैली हुई है। उनके जन्म के समय अंग्रेज छाये थे और उनके पिता पुराने सामंती ढंग से शासन करते थे। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, विरासत में मिलनेवाली 'उदारताहीन सत्ता और सहानुभूतिशून्य शक्ति' से उन्हें घृणा होने लगी। जब तक वह जवान हुए, तब तक भारत आजाद हो चुका था। उनका पूर्वाकलन सही निकला कि 'पुराना सामंती ढांचा गिर रहा है और मेरे पिता की जिंदगी मेरे लिए नहीं है।' तब युवा राजकुमार ने खुद को परिवर्तन के लिए तैयार किया। वह बताते हैं, "मैं राजवंशों में पहला ऐसा व्यक्ति था, जिसने नये जनतांत्रिक ढांचे में खपने के लिए अपने आपको तैयार किया। २२ वर्ष की उम्र में मैं सदर-ए-रियासत चुना गया और इस तरह सामंतवाद से लोकतंत्र की यात्रा का अगुवा बना।"

बहरहाल, कर्ण सिंह के अनुसार यह सब निर्द्वंद्व नहीं हुआ था। लेकिन वह यह भी मानते हैं, "यह कुछ खोने का दुख या पश्चाताप नहीं था। मेरे पास कभी कोई राज्य नहीं था। मैंने हमेशा महसूस किया कि सामंती व्यवस्था मेरी चेतना को विकसित करने में कभी भी सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। सामंती व्यवस्था से निकलना वास्तव में किसी बंधन से छुटकारा पाने जैसा था। अत: लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा प्रवेश अनिच्छा के साथ नहीं, उत्सुकता, सक्रियता और सकारात्मकता के साथ हुआ।"

युवा राजकुमार के लिए यह परिवर्तन आसान तो था, लेकिन उन्हें काफी कीमत चुकानी पड़ी। उनके पिताजी से उनका दुराव हो गया, क्योंकि घटनाओं ने जैसा मोड़ लिया था, उससे उनके पिताजी का दुखी होना स्वाभाविक था। पीढ़ियों के अंतर ने भी पिता-पुत्र के बीच दूरी को बढ़ा दिया।

१९६१ में कर्ण सिंह अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन यात्रा पर गये। अपनी यात्रा के दौरान २४ अप्रैल को जब वह रोम में उतरे, तो भारतीय राजदूत ने उन्हें उनके पिता की मृत्यु की सूचना दी। पिता के साथ बिताये खुशी के दिनों की यादें उनके दिमाग में घुमड़ने लगीं और वह तुरंत वापस लौट आये। वह बताते हैं, "मुझे पक्का विश्वास है कि वह मुझे बेहद प्यार करते थे, तथापि मैं ऐसे प्यार की आशा करता था जैसा मेरा अपने बच्चों के साथ है—बंधनों और तनाव से मुक्त।" बहरहाल, उस व्यक्ति ने जो शासन करने के लिए पैदा हुआ था, ३० वर्ष की उम्र में 'हिज हाइनेस' या 'महाराजा' की पदवी से विभूषित होने के बजाय अपनी पहचान मात्र 'श्री कर्ण सिंह' के रूप में स्वीकार कर ली।

विविध रंग: कर्ण सिंह की जिंदगी को १८-१८ साल के हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहले १८ वर्ष उन्होंने एक राजकुमार की तरह व्यतीत किये। अगले १८ साल उन्होंने जम्मू-कश्मीर की देखभाल में बिताये—पहले राज्य प्रतिनिधि (रीजेंट) की हैसियत से, फिर सदर-ए-रियासत और अंततः राज्यपाल की हैसियत से। तीसरे हिस्से में वह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय रहे। अब चौथे हिस्से में यानी ५४ साल की उम्र में वह राजनीति से आत्मनिर्वासित होकर, विश्व स्तर पर धार्मिक और बौद्धिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लग गये हैं।

उनकी जिंदगी के दूसरे चरण के प्रारंभिक वर्ष कष्टदायक रहे। उस समय आजादी मिलनेवाली थी और काफी उथल-पुथल थी। १९४७ में पाकिस्तान समर्थित पठान कबाइलों का हमला उन्हें अच्छी तरह याद है। बिजली कट गयी थी और सीमा के पास जब भी किसी कस्बे के दुश्मन के हाथ में चले जाने की खबर उनके पिताजी के पास पहुंचती थी, तो वह दुखी हो उठते थे। अंत में उन्होंने भारत से सहायता की अपील की और भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इसके बाद एक स्कूल मास्टर शेख अब्दुल्ला के राजनीतिक क्षितिज पर हंगामा बरपाने पर महाराज हरि सिंह को जम्मू-कश्मीर छोड़कर बंबई में बसना पड़ा। अंततः 'कर्ण सिंह के राजनीतिक गुरु' पं० नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेहरू ने उन्हें (डा० कर्ण सिंह) जम्मू-कश्मीर का राज्य प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। लेकिन इस निराशापूर्ण समय में भी आशाएं थीं। १९ वर्षीय कर्ण सिंह की शादी नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री १३ वर्षीया आशा से हुई। आशा उनके लिए एक समझदार पत्नी साबित हुई। हालांकि अब यह बात सुनकर वह लजाते हैं, लेकिन कर्ण सिंह अपनी पत्नी के सम्मान में प्रेम कविताएं लिखने में कभी नहीं थके। बंबई में उनका विवाहोत्सव (उस मसय उनका आपरेशन हुआ था और वह नेपाल जाने की स्थिति में नहीं थे) काफी धूमधाम से हुआ। पारंपरिक उत्सव के बाद एक बड़ी पार्टी हुई, जिसमें हीरे-जड़ित सोने के गिलासों में भोर तक शैम्पेन

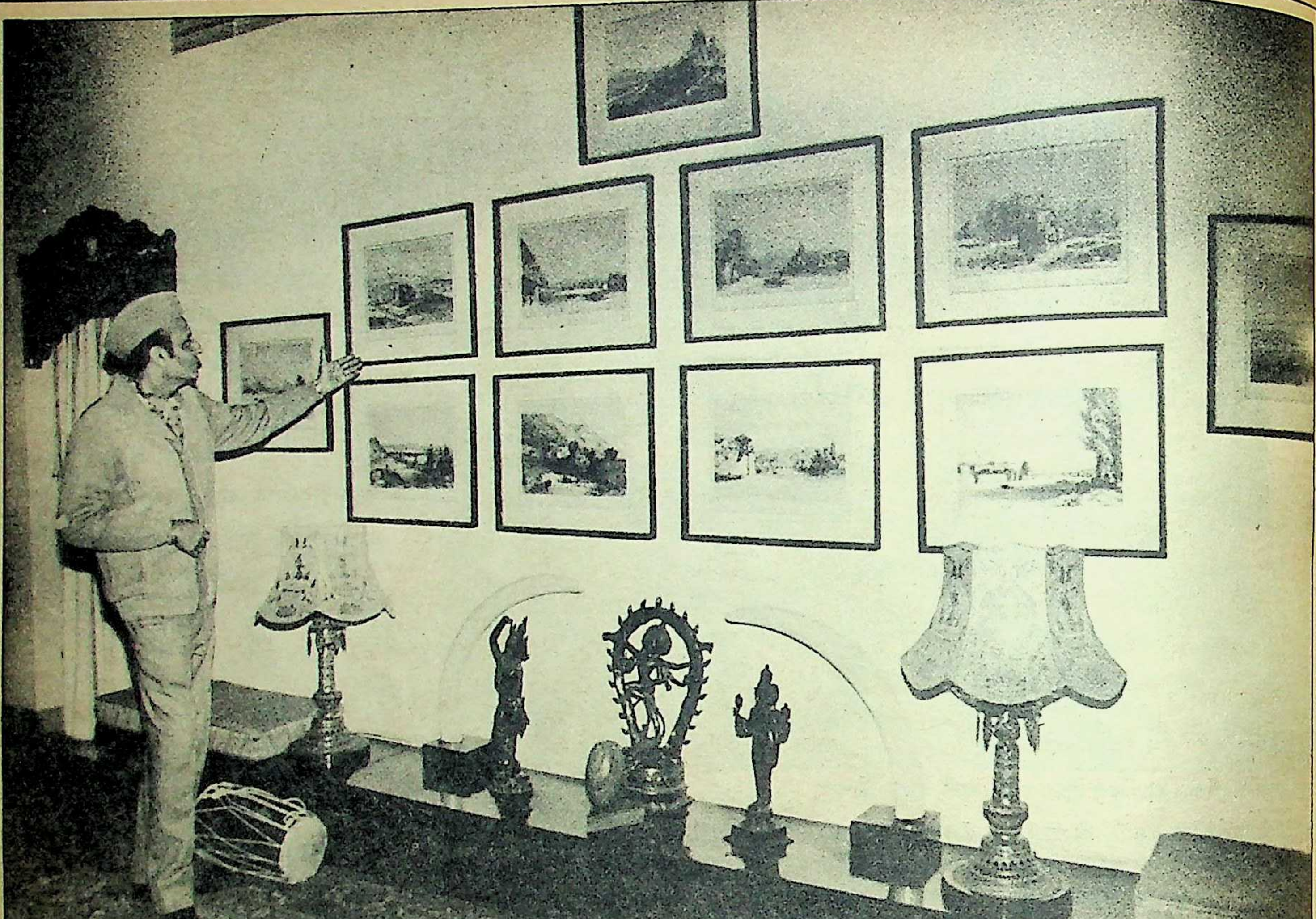

कलानुरागी : कर्ण सिंह

परोसी गयी। जब सभी समारोह समाप्त हो गये, तो युवा जोड़े ने महसूस किया कि केवल आधे घंटे की मुलाकात के सिवाय वे अजनबी थे। कर्ण सिंह कहते हैं, "फिर हम दोनों साथ-साथ बड़े हुए जो बेहद सुखदायी अनुभव रहा। इससे दोनों के बीच बेहतर समझदारी पैदा हुई।"

सर्वाधिक युवा मंत्री : ३६ साल की उम्र में कर्ण सिंह राष्ट्रीय राजनीति में आये और सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। राजनीति शास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी और यह सैद्धांतिक अनुभव १० वर्ष तक मंत्रिमंडल में रहने और ८ साल तक सत्ता के बाहर रहने से और संवर्द्धित हुआ। वह महसूस करते हैं कि राजनीति मानवीय रिश्तों और कार्यों से सीधे जुड़ी है और इससे उन्होंने केवल प्रशासन और राजनीति ही नहीं सीखी, बल्कि लोगों के अहं को भी समझा। कूटनीति के महत्व को भी उन्होंने समझा, लेकिन थोड़ी देर से। वह बताते हैं, "मेरे लिए कोई वर्जना नहीं थी, इसलिए मैंने अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त किये, लेकिन लोगों ने यह सोचा कि यह युवा कुछ ज्यादा ही स्वच्छंद है।" यद्यपि उनके कैबिनेट सहयोगियों ने कभी अपना विरोध प्रकट नहीं किया, परंतु पार्टी के युवा तुर्कों ने हमेशा शाही पृष्ठभूमि के कारण उनकी खिलाफत की।

कश्मीर के विशाल और भव्य 'व्हाइट हाउस' के वातावरण में वह बड़े हुए थे। कर्ण सिंह के अनुसार, "कई समकालीन राजकुमारों के महलों की तरह हमारा महल नहीं है। हमारा महल पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में करीने से बना है और पीछे जंगल शुरू हो जाता है। मेरे पिता ने एक बार मुख्य लान में चीता मारा था।" हीरे-जवाहरात से खेलने की यादें अब मलिन पड़ गयी हैं, मगर बड़ी-बड़ी हस्तियों के दौरे उन्हें अभी भी रोमांचित कर देते हैं।

पुरानी यादें : वायसराय माउंटबेटन के साथ दो मजेदार घटनाएं घटीं। कर्ण सिंह सुनाते हैं, "भोज इत्यादि के बाद पिताजी एक घंटी बजाते थे जो कि एक टेबिल में लगी थी। इस घंटी के बजने के बाद बैंड पार्टी 'गाड सेव द किंग' (राजा की खुदा खैर करे) की धुन निकालते थे। एक बार माउंटबेटन का घुटना इस घंटी से टकरा गया और बैंड पार्टी ने वायसराय के सम्मान में बजायी जाने वाली धुन शुरू कर दी। लिहाजा हर एक को चिकन करी बीच में ही छोड़कर उठ जाना पड़ा।"

"दूसरी घटना वायसराय से वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय कराने के दौरान घटी। महाराजा हरि सिंह ने किसी गलती से बचने के लिए सभी अफसरों को एक सूची में दर्ज नामों के क्रम से खड़े होने के आदेश दिये। किसी कारण वश एक अफसर ने अपना स्थान बदल दिया। लिहाजा, महाराजा ने हर अफसर का परिचय गलत नाम लेकर करवाया।"

१८ वर्ष की उम्र में जब कर्ण सिंह ग्रेजुएट भी नहीं थे, रियासत के प्रमुख बना दिये गये। लेकिन, इसके बावजूद उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंकों से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पी॰एच-डी॰ भी की। शायद वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने जिस विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की, उसी के कुलपति भी थे।

डा॰ कर्ण सिंह द्वारा बौद्धिकता पर जोर देने की व्याख्या यह कह कर की जा सकती है कि यह उनके लिए एक प्रकार से खोये हुए राज्य का विकल्प है। वह कहते हैं, "दरअसल यह बड़ा साम्राज्य है। जैसी कि कहावत है : राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सारे विश्व में।" वह आगे कहते हैं, "लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान होने का दावा कर रहा हूं।"

आध्यात्मिकता, बौद्धिकता और सीखने की इच्छा उनकी जिंदगी के वर्तमान चरण में और भी

ज्यादा दिखायी पड़ती है। इस समय वह राजनीति से बाहर हैं, मगर सार्वजनिक जीवन से सीधे जुड़े हैं। वह बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं और समारोहों तथा धार्मिक उत्सवों में भाषण देते हैं। कर्ण सिंह बताते हैं, "मेरी आध्यात्मिक भू अल्मोड़ा के श्रीकृष्ण प्रेम जैसे अद्भुत लोगों से प्रेरित है। श्रीकृष्ण प्रेम अंग्रेज हैं और मेरे लिए वह महत्वपूर्ण प्रेरणा-स्रोत रहे हैं।"

हिंदूवाद में कर्ण सिंह की रुचि बचपन से ही रही है। १९६१ में उन्होंने श्री अरविंद घोष पर पी०एच-डी० की थी। इस समय उनकी धार्मिक रुचियां राष्ट्रीय सीमाएं पार कर गयी हैं। वह स्पष्ट करते हैं, "मैं क्रमशः विश्व-दर्शन की ओर बढ़ रहा हूं, जिससे इस नाभिकीय युग में मनुष्य जाति, धर्म आदि के बंधनों को तोड़ कर जीने लायक परिस्थितियां पैदा कर सके।"

एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से मैंने राजकुमारों को समझाने की भरसक कोशिश की कि इसमें पैसे की नहीं, सिद्धांत की बात है। मैंने एक मसौदा तैयार किया, जिसके तहत अंततः उन्हें समान धनराशि देने की बात थी, लेकिन राजकुमारों के नेताओं ने कड़ा रवैया अपनाया, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और मुझे भी उनसे अलग होना पड़ा।

हिंदूवाद के अलावा कर्ण सिंह को संस्कृति, संगीत, नृत्य और चित्रकला से भी लगाव है। संगीत प्रेमी वह बचपन से ही थे, जब उनकी मां ढोलकी बजाकर गाती थीं और बांदियां उनके साथ टेर लगाती थीं। वह बताते हैं, "बचपन में सुने डोगरी गीतों की यादों ने मेरे पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है।" इसी संगीत प्रेम के चलते उनका रुझान कानसेन (श्रोता) से तानसेन (प्रसिद्ध गायक) बनने की ओर हुआ। उनकी मां जब मृत्यु शय्या पर पड़ी थी, तो कर्ण सिंह के भक्ति तथा शास्त्रीय संगीत से उन्हें अपूर्व शांति मिलती थी।

कर्ण सिंह के अनुसार उनकी जीवन-पद्धति बरसों से एक जैसी है। उनके अनुसार, "मैं कश्मीर में भी कभी राजकुमारों की तरह नहीं रहा। दिल्ली में मेरा मकान मेरे राजनीति में आने के बहुत पहले पचास के दशक में बना था। राजनीति में आने के बाद से मैं उसी में रह रहा हूं। यह आरामदायक है। लेकिन उसमें कहीं भी सामंती सजावट, आडंबर और दिखावा नहीं है। नौकर अभी भी काफी हैं, परंतु उनकी संख्या पहले से बहुत कम हो गयी है।

खास से आम: श्रीनगर में उनका महल काफी भव्य और सजावटपूर्ण है। जगह-जगह पर यूरोपीय तथा चीनी वस्तुओं से सजा है। गलियारों और बरामदों में कीमती कालीन बिछे हैं। कश्मीरी कालीनों को छोड़कर बाकी सामान यूरोपीय है। उसमें से बहुत-सा सामान दिल्ली में धनिकों की बस्ती चाणक्यपुरी में स्थित कर्ण सिंह के निवास में सजा दिया गया है। दिल्ली में शाही पृष्ठभूमि का संकेत करने वाली एक मात्र ऊपरी चीज है—शाही घराने का प्रतीक 'सूर्य' जो मुख्य दरवाजे पर लगा है। हालांकि उनके घर में बड़ा लान, स्विमिंग पूल और सुंदर बैठक हैं। मगर जिस तरह के महलों में उनका लालन-पालन हुआ है, उससे इसका कोई मुकाबला नहीं है।

अध्यात्म और धर्म की गुत्थियों में व्यस्त: कर्ण सिंह

सामंतवाद विरोधी उनकी गतिविधियों, खासतौर पर प्रिवीपर्स के मामले में उनके रवैये—ने उन्हें राजाओं की बिरादरी से अलग कर दिया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। कर्ण सिंह बताते हैं, "एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से मैंने राजकुमारों को समझाने की भरसक कोशिश की कि इसमें पैसे की नहीं, सिद्धांत की बात है। मैंने एक मसौदा तैयार किया, जिसके तहत अंततः उन्हें समान धनराशि देने की बात थी, लेकिन राजकुमारों के नेताओं ने कड़ा रवैया अपनाया, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और मुझे भी उनसे अलग होना पड़ा। मैंने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं उनका नहीं, आम लोगों का नेतृत्व कर रहा था।"

कर्ण सिंह बताते हैं कि खिताब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कश्मीर के साथ वह अपना रिश्ता अटूट मानते हैं, इसलिए वह हर साल कुछ समय के लिए कश्मीर जाते हैं। कश्मीर और परिवार से उनके भावनात्मक रिश्ते हैं।

व्यावसायिक दृष्टि से भी उनका कश्मीर से रिश्ता है। १९५४ में उनका परिवार होटल व्यवसाय से उस समय जुड़ गया, जब ओबेराय होटल के एम०एस० ओबेराय ने गुलाब भवन पट्टे पर मांगा। श्रीनगर स्थित मुख्य महल गुलाब भवन उस समय उपयोग में नहीं आ रहा था। उनके दोनों पुत्रों ने जल्दी शिक्षा ग्रहण करने के बाद पूरी तरह से व्यावसायिक नजरिया अख्तियार कर लिया है। उनके होटल साम्राज्य के भविष्य में तेजी से विकास करने की उम्मीद है।

शायद अपने माता-पिता से पर्याप्त लाड़-प्यार न मिल पाने के कारण कर्ण सिंह अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देते हैं। अपनी रूढ़ और अनुशासित जिंदगी के ठीक उलटे उन्होंने अपने बच्चों को काफी स्वतंत्रता दे रखी है। अपनी पुत्री ज्योति के बारे में वह बताते हैं, "वह मुझसे भी ज्यादा सामंतवाद विरोधी है। उसने न केवल गैरशाही परिवार में शादी की, बल्कि दिल्ली के एक कालेज में दर्शनशास्त्र की व्याख्याता भी है। वह मेरी सबसे बड़ी आलोचक भी है। यह अच्छा ही होता है कि कोई नजदीकी आपके कार्यों के बारे में सवाल करे।"

जहां तक पुत्रों का प्रश्न है वे व्यक्तिवादी हैं और सबके विचार अलग-अलग हैं। बड़े पुत्र विक्रमादित्य सामंती विचारों वाले हैं। कर्ण सिंह बताते हैं, "मैं सामंती चिन्हों जैसे साफा आदि का उपयोग नहीं करना चाहता था। मैं नहीं सोचता कि किसी रास्ते पर चलकर पीछे मुड़ना चाहिए। लेकिन मेरी तरह विक्रमादित्य के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। विक्रम का तर्क है, "मैं पिताजी के ठीक विपरीत दिशा में जा रहा हूं। मैं उनका अंधानुकरण नहीं करूंगा।" ■

अमरीकी चुनाव

'महान मंगलवार'

इस वर्ष अमरीका में होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। भारत के लिए यह चुनाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महाशक्ति से उसके भावी संबंध बहुत कुछ नये राष्ट्रपति की नीतियों पर निर्भर होंगे। हालांकि यह उम्मीद करना बेकार है कि कोई भी राष्ट्रपति अमरीकी विदेश नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगा, फिर भी यह तसल्ली की बात है कि नया राष्ट्रपति कम-से-कम हर महत्वपूर्ण मुद्दे का एक नयी नजर से अध्ययन करेगा तथा पूर्वग्रहों से मुक्त होगा। पाकिस्तान और चीन के साथ उलझे संबंधों के कारण भी भारत इस चुनाव के नतीजे का उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा।

हालांकि मुख्य चुनाव ८ नवंबर को होगा, पर चुनाव प्रक्रिया फरवरी से ही आरंभ हो गयी है। इन नौ महीनों में अमरीकी राजनीतिक मंच पर अनेक नाटकीय परिस्थितियां आयेंगी और ह्वाइट हाउस में रहने के अरमान संजोये कई दावेदार इन परिस्थितियों से जूझेंगे। राष्ट्रपति-पद की इस दौड़ में कई धावक तो राह में ही छूट जायेंगे। कुछेक सौभाग्यशाली ही अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां से 'व्हाइट हाउस' एक छलांग की दूरी पर होगा। यह विशिष्ट चुनाव प्रक्रिया, जितनी लंबी है, उतनी ही जटिल भी है।

राष्ट्रपति मैं बनूंगा ! : जार्ज बुश

अमरीका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं: सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी तथा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों दल राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार 'प्राथमिक चुनावों' और राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा चुनेंगे। 'प्राथमिक चुनावों' में उन प्रतिनिधियों का चयन होता है जो राज्य और बाद में राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों में राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार चुनते हैं। इस प्रकार, जहां एक तरफ एक 'इलेक्टोरल कालेज' का गठन होता है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों का चयन भी हो जाता है।

ये 'प्राथमिक चुनाव' या 'स्टेट प्राइमरीज' देश के सभी ५० राज्यों में भिन्न-भिन्न अवधि में होते हैं।

'प्राथमिक चुनावों' की श्रृंखला में अब तक जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहा है, वह 'सुपर ट्यूज्डे' या बीबीसी के शब्दों में 'महान मंगलवार' का दिन था। मंगलवार, मार्च ८ तारीख को बीस राज्यों में एक साथ 'प्राथमिक चुनाव' हुए। इनमें से १४ राज्य दक्षिणी अमरीका में थे। इन चुनावों में रिपब्लिकन दल के उम्मीदवार तथा उपराष्ट्रपति जार्ज बुश को अपनी पार्टी के अन्य प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारी बढ़त हासिल हुई। दूसरे स्थान पर, परंतु बुश से काफी पिछड़े हुए थे राबर्ट डोल। लेकिन डेमोक्रेटिक दल से किसी एक प्रत्याशी को साफ बहुमत हासिल नहीं हुआ। मेसेचुसेट्स राज्य के गवर्नर, माईकेल डुकाकिस, हालांकि अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों—जेसी जैक्सन और अलबर्ट गोर—से कुछ आगे जरूर निकल गये।

'सुपर ट्यूज्डे' की जीत बुश के लिए एक भारी सफलता मानी जाती है। विशेषकर इसलिए कि इन चुनावों के पूर्व आयोवा राज्य में उन्हें राबर्ट डोल के हाथों मात खानी पड़ी थी। इस हार के पश्चात बुश हैंपशायर राज्य में जीते तो जरूर, लेकिन उनके वर्चस्व की मोहर 'सुपर ट्यूज्डे' के दिन ही लगी। अमरीका के दक्षिणी राज्य रिपब्लिकन दल के गढ़ माने जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बुश को विजय दिलाने में राष्ट्रपति रीगन की व्यक्तिगत लोकप्रियता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जहां तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का प्रश्न है, डुकाकिस ने अपनी जीत से यह साबित कर दिया है कि वह केवल राज्य स्तरीय नेता नहीं हैं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं। अपने राज्य मेसेचुसेट्स के अलावा उन्होंने फ्लोरिडा और टेक्सास के साथ पांच दक्षिणी राज्यों में भी जीत हासिल की।

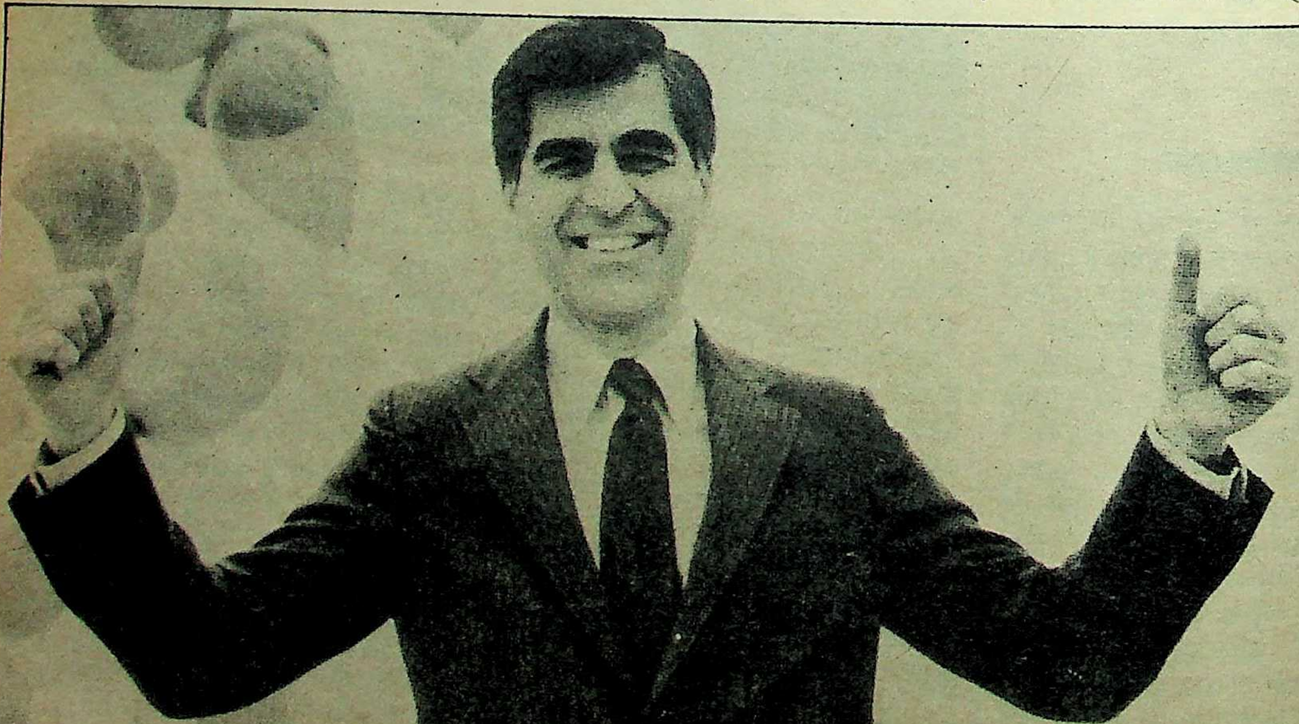

राष्ट्रीय छवि की तलाश : माइकल डुकाकिस

मेरीलैण्ड और रोड आइलैण्ड में जीतकर डुकाकिस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आगमन का डंका पीट दिया है।

इसके विपरीत गोर, दक्षिण-निवासी होते हुए भी अपेक्षित सफलता नहीं पा सके। उन्हें केवल पांच राज्यों में बढ़त मिली, जिसमें ३५२ प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि वह 'ह्वाइट हाउस' तक की लंबी दूरी तय कर पायेंगे।

जेसी जैक्सन निस्संदेह एक लोकप्रिय नेता हैं। विशेषकर, अमरीका के अश्वेतों में उनकी खासी धाक है। जैक्सन मानवाधिकार संबंधी संघर्षों के लिए मशहूर हैं। 'सुपर ट्यूज्डे' के चुनावों में उन्होंने अपना स्थान दृढ़ कर लिया था। लेकिन प्रेक्षकों के अनुसार ऐसा नहीं लगता है कि अमरीकावासी एक अश्वेत को अपना राष्ट्रपति चुनेंगे, चाहे वह कितना ही काबिल क्यों न हो।

तमाम विपक्षी प्रयासों के बावजूद लगता है, बुश अपनी छवि बनाये रखने में कामयाब रहे हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति रीगन की छवि इस कांड में मटियामेट हो गयी है।

सवाल उठता है कि 'सुपर ट्यूज्डे' में ऐसा क्या था कि उसके परिणामों को इतना महत्व दिया जा रहा है? एक तो यह कि ऐसा पहली बार हुआ था कि बीस राज्यों में एक साथ 'प्राथमिक चुनाव' हुए हों। इन चुनावों में दोनों दलों के लगभग एक-तिहाई प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। दूसरा महत्व का कारण था इन राज्यों पर रिपब्लिकन पार्टी की पारंपरिक पकड़। लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या ईरान-कांट्रा सौदेबाजी से रिपब्लिकन दल की छवि को नुकसान पहुंचा है? परिणामों से यह भय निराधार साबित हुआ है। तमाम विपक्षी प्रयासों के बावजूद लगता है, बुश अपनी छवि बनाये रखने में कामयाब रहे हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति रीगन की छवि इस कांड में मटियामेट हो गयी है। खुद बुश अपनी विजय पर इतने प्रफुल्लित हुए कि उन्होंने घोषणा की: "मैं अमरीका का राष्ट्रपति बनने वाला हूं!" बुश के इस वक्तव्य से और उम्मीदवार भले ही सहमत न हों, यह बात सभी स्वीकारते हैं कि चुनाव प्रणाली बहुत लंबी और जटिल है। इसके बावजूद प्रणाली के आलोचक, दो कारणों से कम ही मिलेंगे: एक, इस प्रणाली द्वारा हर उम्मीदवार को अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उचित अवसर मिलता है—व्यक्तिगत रूप से, विज्ञापनों के जरिए, टीवी कार्यक्रमों के द्वारा, इत्यादि। दूसरा कारण है, उम्मीदवारों की आर्थिक समृद्धि जो इस तरह के चुनाव-अभियानो के लिए आवश्यक है। और फिर, जैसा कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, वाल्टर मांडेल ने कहा है, "यदि आप राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो चार वर्षों तक इसकी तैयारी में इतना लीन होना पड़ेगा कि आपके पास कुछ और करने का वक्त ही नहीं रहेगा। चार वर्षों तक हर दिन १४-१८ घंटों की मेरी दिनचर्या रही है।"

रूस में भी सांप्रदायिकता

भारतीयों के लिए सांप्रदायिक, जातीय और भाषायी दंगे नयी चीज नहीं हैं। लेकिन रूस जैसे साम्यवादी देश में भी यदि ऐसे ही दंगे होते हैं, तो आश्चर्य होता है। जब से रूसी नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने 'लौह परदे' को थोड़ा-सा-उठाया है, तब से वहां भी क्षेत्रीय और जातीय भेदभाव की शिकायतें करने की हिम्मत पैदा हो गयी है।

यह आम धारणा है कि वामपंथी व्यवस्था में जातीय अथवा सांप्रदायिक दंगे इसलिए नहीं होते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा राजनीतिक ढांचा भी कुछ इस प्रकार का होता है कि संकीर्णतावादी ताकतें सिर नहीं उठा पातीं। यह भी नहीं है कि नागरिकों को अपना प्रतिवाद जताने की वैसी स्वतंत्रता नहीं होती, जैसी गैर साम्यवादी व्यवस्था में होती है।

लेकिन जकड़बंद व्यवस्था में ढील के कुछ संकेत गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद दिखे हैं। उनकी उदार नीतियों के कारण ही अब तक दबी कई आवाजें बुलंद होने लगी हैं। छिपी विसंगतियां उभर कर सामने आने लगी हैं। लेकिन जिस तथ्य ने सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह था रूस में पिछले कई दशकों से नीचे-नीचे सुगबुगाते जातीय मतभेद का फूट पड़ना। ऐसे क्या कारण थे कि एक कट्टर साम्यवादी अथवा नास्तिक व्यवस्था में जातीयता पनप उठी?

बढ़ता सांप्रदायिक असंतोष

रूसी नेता गोर्बाचेव ने अपनी उदारपंथी नीतियों से जहां एक ओर विश्व की वाहवाही लूटी है; वहीं इन नीतियों की ओट में देश में भड़के जातीय दंगों से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। मार्च के प्रथम सप्ताह में सोवियत रूस के दो गणराज्यों, आरमीनिया और अजरबैजान के मध्य झड़प में कम-से-कम तीस व्यक्ति मारे गये और कई अन्य घायल हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात रूस में हुए जातीय रक्तपात की यह सबसे गंभीर घटना है।

अजरबैजान और आरमीनिया का झगड़ा पुराना है। दोनों गणराज्यों में बाहर से आकर बसे रूसियों का बहुमत है—अजरबैजान में शिया मुसलमानों और आरमीनिया में ईसाइयों का। इनके मध्य मतभेद के दो प्रमुख कारण हैं—एक, दोनों की भिन्न धार्मिक आस्थाएं और दूसरा, नागोर्नी काराबख क्षेत्र जो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन जिस पर आरमीनियायी अपना हक मानते हैं। हालांकि यह सत्य है कि उस क्षेत्र में आरमीनियायियों का बहुमत है, लेकिन रूसी अधिकारियों का कहना कि अब नागोर्नी काराबख को आरमीनिया में जोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। जहां तक धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है, आरमीनियायियों का कहना है कि यदि रूसी सैनिक न मौजूद होते, तो मुसलमान उन पर हावी होते और ईसाइयों को अजरबैजान से हमेशा खतरा बना रहता। जो भी हो, गोर्बाचेव के 'खुलेपन' का पूरा-पूरा फायदा इन मुद्दों के उठानेवालों को मिला। इस महीने की शुरुआत में हजारों आरमीनियायियों ने अपनी राजधानी, येरेवान में अहिंसात्मक प्रदर्शन किया और मांग की कि नागोर्नी काराबख उन्हें सौंपा जाये। लेकिन, इसके कुछ दिनों पश्चात इसी क्षेत्र में हिंसात्मक दंगे तब भड़क उठे, जब ईसाई आरमीनियायी और मुसलमान अजरबैजान आपस में टकराये।

रूस में अधिकतर जातीय मतभेद ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों से हैं। सोवियत रूस में पंद्रह गणराज्य सम्मिलित हैं, जिनकी अलग-अलग भाषा एवं संस्कृति है। इनमें आरमीनिया सबसे छोटा गणराज्य है, जिसका विलय रूस में १९२० में हुआ था। हर राज्य अपना अलग व्यक्तित्व, अपनी विशिष्टता बनाये रखने में प्रयत्नशील रहा है। स्वाभाविक है कि इन प्रयत्नों के दौरान उनकी एक दूसरे से झड़प हो जाती थी। परंतु पिछले ६७ वर्षों से रूसी सत्ता इन मतभेदों के अस्तित्व को

पहचानने से इनकार करती आयी है। शायद इस उम्मीद में कि साम्यवादी चादर से ढंके जाने के बाद हर रूसी अपनी पारंपरिक आसक्तियों को भुलाकर 'रूस जिंदाबाद' के नारे लगाने लगेगा। उन्हें शायद यह भी विश्वास हो गया था कि जिस 'नास्तिक' सामाजिक प्रणाली का निर्माण किया गया था, उसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। ये धारणाएं कितनी निराधार थीं, इसका खुलासा गोर्बाचिव की उदार नीतियों ने कर दिया है। यों दबी भावनाएं उभाड़ना इन नीतियों का मकसद नहीं था।

इन जातीय दंगों के परिणामस्वरूप रूस में कोई बड़ा राजनीतिक संकट भले ही पैदा न हो, गोर्बाचिव की सुधार-नीतियों पर प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही। यदि इन दंगों की उग्रता कायम रही, तो गोर्बाचिव संभव है, खीझकर सुधारवाद त्याग दें और पुराने ढर्रे पर चलने लगें। यह भी हो सकता है कि सरकार इन दंगों के हल ढूंढ़ने में इतनी उलझ जाये कि उसका ध्यान उदारपंथी नीतियों से ही हट जाये।

विडंबना यह भी है कि गोर्बाचिव के 'पेरेस्त्रोइका' की नीति ने कहीं-कहीं पर जातीय दंगों की नींव रखी। जब दिसंबर १९८६ में उन्होंने कजाकिस्तान में एक मूल निवासी नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों पर निकाल बाहर किया और उसके स्थान पर एक रूसी की नियुक्ति की, तो वहां दंगा भड़क उठा, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। पिछले वर्ष उन्होंने एक आरमीनियायी नेता की कार्य प्रणाली की कड़ी आलोचना की थी, जिसके फलस्वरूप वहां के निवासी गोर्बाचिव के खिलाफ हो गये।

रूसी नेता के 'ग्लासनोस्त' की भी आलोचना इन गणराज्यों में हो रही है। अल्पसंख्यक वर्ग की शिकायत है कि रूसी सत्ता ने उन्हें वही कुछ कहने की छूट दी है जो वे सुनना चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसे 'खुलेपन' का कोई लाभ नहीं है।

ऐसी बात नहीं है कि सरकार हाथ-पर-हाथ रखे बैठी है। कम-से-कम उदारपंथी नीतियों से यह लाभ हुआ है कि अल्पसंख्यक बीन बजायें, तो भैंस उसकी ओर देखेगी जरूर। अल्पसंख्यक वर्ग को खुश रखने के मकसद से हाल में नागोर्नी काराबख के रूसी नेता को बरखास्त कर एक आरमीनियायी की नियुक्ति की गयी थी। वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार की भी छूट दे दी गयी है। संकेत मिले हैं कि इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए गोर्बाचिव इस वर्ष केंद्रीय समिति की बैठक भी बुलायेंगे।

इन प्रयासों के जो भी परिणाम निकलें, यह बात तो साफ हो गयी है कि राष्ट्रीय एकता के जिस अटूट ढांचे का प्रचार रूस करता आ रहा है, वह ढांचा अब वाकई चरमरा रहा है।

—राजेश सिंह

बांगलादेश-पाकिस्तान

तीन महिलाओं का जेहाद

क्या जंग जारी रहेगी ? : बेनजीर भुट्टो

एशियाई देशों की राजनीति में महिलाओं की भागेदारी कम नहीं रही है। यद्यपि ज्यादातर महिला नेता संपन्न वर्ग से आयीं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली, मगर इसके बावजूद उनकी योग्यताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, श्रीलंका की पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रमुख विपक्षी पार्टी की नेता सिरीमाओ भंडारनायके, इस्राइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर और फिलीपींस की राष्ट्रपति कोराजोन अकीनो के नाम मिसाल के तौर पर गिनाये जा सकते हैं। हाल में तीन और महिला नेताओं के नाम उभर कर आये हैं। ये हैं—पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो और बांगलादेश की शेख हसीना वाजेद तथा बेगम खालिदा जिया। इन तीनों ही सियासतदानों ने फौजी हुक्मरानों की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो का आंदोलन जरूर थमा हुआ सा लगता है, मगर बांगलादेश की इन दो जुझारू नेताओं का जेहाद दिनोदिन जोर पकड़ता जा रहा है। बेनजीर, हसीना और जिया इन तीनों नेताओं में एक समानता यह भी है कि ये तीनों ही अपने देश के प्रमुखों से किसी-न-किसी रूप में जुड़ी रही हैं। बेनजीर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की और हसीना बांगलादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री हैं। खालिदा जिया बांगलादेश के सैनिक शासक जियाउर्रहमान की बेवा हैं।

बेनजीर : आकर्षक व्यक्तित्व की धनी बेनजीर भुट्टो प्रगतिशील विचारोंवाली मानी जाती हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामी देश में जहां महिलाओं को नाम मात्र के भी अधिकार हासिल नहीं हैं, बेनजीर का आजादी से सियासत करना उनके प्रगतिशील सोच को ही जाहिर करता है। उनका थोड़ा-बहुत रुझान वामपंथी विचारधारा की ओर भी है। हाल में उनकी लिखी पुस्तक को एक अमरीकी प्रकाशक ने इस बिना पर छापने से मना कर दिया था कि उसमें कुछ ज्यादा ही वामपंथी बातें की गयी हैं।

देखा जाये तो बेनजीर भुट्टो का सियासती अनुभव केवल दो साल का है। उन्होंने १९८६ में ही सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्हें अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम और उनकी पीपुल्स पार्टी का फायदा जरूर मिला है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। १९७१ में याहया खान के इस्तीफा देने के बाद भुट्टो प्रधानमंत्री बने थे। १९७९ में भुट्टो को फांसी दे दी गयी थी, जिसके बाद उनकी पत्नी नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बागडोर संभाल ली थी। लेकिन बीमारी और लंबी कैद से ऊबकर वह लंदन चली गयी थीं। उनके दो बेटे पहले से ही निर्वासित थे। बेनजीर भुट्टो ने भी कैद से छूटने के बाद लंदन की राह पकड़ ली।

आकर्षक व्यक्तित्व की धनी बेनजीर भुट्टो प्रगतिशील विचारोंवाली मानी जाती हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामी देश में जहां महिलाओं को नाममात्र के भी अधिकार हासिल नहीं हैं, बेनजीर का आजादी से सियासत करना उनके प्रगतिशील सोच को ही जाहिर करता है। उनका थोड़ा रुझान वामपंथी विचारधारा की ओर भी है।

जनरल जिया की इजाजत मिलने के बाद अप्रैल, १९८६ में बेनजीर पाकिस्तान वापस लौट आयीं और १८ मई, १९८६ को पीपुल्स पार्टी की सह अध्यक्ष चुन ली गयीं। तुरंत ही उन्होंने जिया विरोधी अभियान छेड़ दिया। शुरुआत में उन्हें जो सफलताएं मिलीं, उनसे एकबारगी लगा कि वह जिया का तख्ता उलटने में कामयाब हो जायेंगी, मगर फिर जिया ने बड़ी ही चालाकी से स्थिति उलट दी। उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। बेनजीर ने चुनाव का बायकाट करने की अपील की, मगर उन्हें आंशिक सफलता ही मिल पायी। चुनाव के बाद जिया ने संवैधानिक रूप से अपनी स्थिति

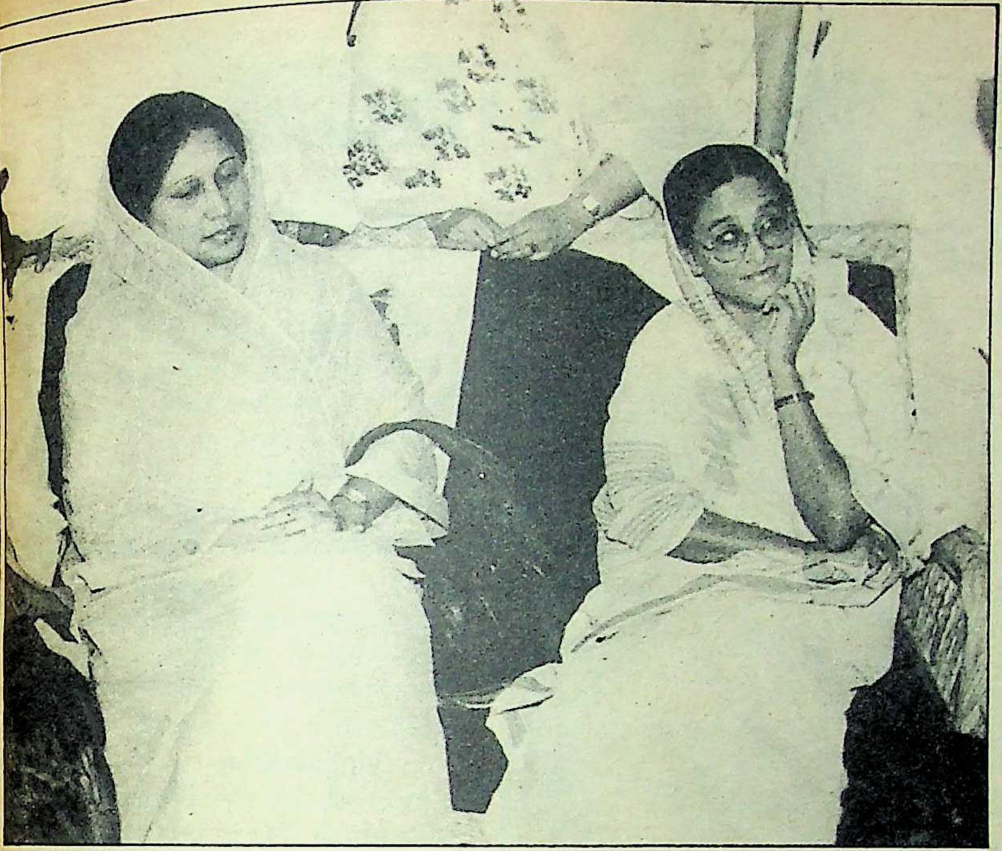

तानाशाही के खिलाफ जेहाद : बेगम खालिदा जिया और हसीना वाजिद

मजबूत कर ली और फिर मार्शल ला उठाने का नाटक भी कर डाला। इन सब बातों से बेनजीर का आंदोलन टांय-टांय फिस्स हो गया और उनके पास सिवाय अगले चुनाव का इंतजार करने के कुछ भी बाकी नहीं रहा।

आंदोलन धीमा पड़ने के साथ ही पीपुल्स पार्टी में भी फूट पड़ने लगी। पंजाब शाखा के अध्यक्ष जहांगीर बद्र ने १२ साथियों सहित पार्टी छोड़ दी है। इसी तरह पार्टी के एक और प्रमुख नेता गुलाम मुस्तफा जटोई ने भी बेनजीर से अपने मतभेदों को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीपुल्स पार्टी अपने मुख्य गढ़ पंजाब और सिंध में ही बिखरी हुई है। इसी का नतीजा था कि हाल में हुए स्थानीय चुनावों में उसे अपने घर में ही कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। फूट की एक वजह पार्टी में वामपंथियों की अधिकता भी बतायी जाती है। लेकिन बेनजीर ने हाल में अफगानिस्तान मुद्दे पर सोवियत संघ की खिंचाई करके अमरीका का सहयोग-समर्थन हासिल करने का मंशा भी जाहिर किया है।

हाल में हुई बेनजीर की शादी भी काफी चर्चा का विषय बनी थी। शादी उनके लिए लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी समाज में कुआरी महिलाओं का सियासत में दखल अच्छा नहीं माना जाता। शादी के बाद इस मामले में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ शादी के बाद उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। फलस्वरूप आज जितना वक्त वह राजनीति को दे,पायेंगी इसमें शक है। यदि वह इन जिम्मेदारियों से बच सकीं, तो निश्चित रूप से उन्हें शादी का फायदा मिल सकता है। बेनजीर का अपनी पार्टी और पाकिस्तानी जनता में 'करिश्माई' प्रभाव है। उनमें गजब की सांगठनिक क्षमता भी है। मगर इस सबकी असली परीक्षा अब १९८९-९० में होने वाले आम चुनावों में ही हो सकेगी।

वाजेद और खालिदा : बंगलादेश की हसीना वाजेद और खालिदा जिया एक-दूसरे से बिलकुल विपरीत होते हुए भी एक ही मंच से राष्ट्रपति इरशाद को हटाने का अभियान छेड़े हुए हैं। आठ विपक्षी दलों के गठबंधन में हसीना की अवामी लीग और खालिदा की नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं।

इन दोनों नेताओं में रहन-सहन, विचारधारा या राजनीतिक अनुभव के स्तर पर कोई समानता नहीं है। ४० वर्षीय हसीना वाजेद बहुत सादा जीवन जीती हैं। उनके पिता मुजीबुर्रहमान की तरह उन्हें भी वामपंथी रुझानों वाला माना जाता है। उनका राजनीति में प्रवेश अचानक नहीं हुआ था। अपने छात्र जीवन में ही वह राजनीति में सक्रिय रही थीं। अवामी लीग की छात्र शाखा से भी वह संबद्ध रहीं, मगर १९६९ में शादी के बाद यह सिलसिला टूट गया। १९७५ में जिस समय उनके पिता की हत्या कर दी गयी थी, वह अपने परिवार के साथ पश्चिम जर्मनी में थीं। वहां से लौटने के बाद १९८० तक वह भारत में रहीं। इसके बाद बांगलादेश जाकर उन्होंने अवामी लीग का नेतृत्व संभाला।

हसीना के ठीक विपरीत ४३ वर्षीय खालिदा का राजनीति में पहले कोई दखल नहीं था। १९८१ में पति जियाउर्रहमान की हत्या हो जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। राजनीति का कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने बड़ी जल्दी बांगलादेश की राजनीति में अपनी पकड़ बना ली। किसी भी मामले में वह हसीना वाजेद से पीछे नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण जलसों में वह ज्यादा भीड़ जोड़ने में भी सफल रहती हैं।

'इरशाद हटाओ आंदोलन' छेड़ने के पहले तक दोनों नेताओं का सुर-ताल अलग-अलग हुआ करता था। देश में किस प्रकार की शासन पद्धति हो इसी में दोनों के गहरे मतभेद थे। हसीना संसदीय प्रणाली की हिमायती थीं, तो खालिदा अपने पति के द्वारा स्थापित की गयी राष्ट्रपति प्रणाली को ही जारी रखना चाहती थीं। ये मतभेद अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा १९८६ में इरशाद द्वारा आयोजित आम चुनाव में भी दोनों नेताओं ने विपरीत रुख अपनाया था। हसीना की अवामी लीग ने इन चुनावों में खुलकर हिस्सा लिया था, जबकि खालिदा की बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार का आह्वान किया था।

गत १० नवंबर को इन दोनों नेताओं द्वारा शुरू किये गये 'इरशाद हटाओ आंदोलन' को जनता का पर्याप्त सहयोग और समर्थन मिला। जमायते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ने भी इरशाद का दामन छोड़ दिया। इस व्यापक विरोध के फलस्वरूप ही इरशाद को इमर्जेंसी लगानी पड़ी। इरशाद ने आम चुनाव की घोषणा की, मगर सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। व्यापक हिंसा और विरोध के बावजूद गत तीन मार्च को चुनाव संपन्न हो गये, जिसमें इरशाद की जातीय पार्टी ने ३०० में से (चुनाव २९७ सीटों के लिए हुआ) २३८ सीटें जीतीं।

अब इरशाद ने गद्दी बचाने का सबसे घटिया तरीका इस्तेमाल करना तय किया है। शासक वर्ग धर्म को संरक्षण किसलिए देता है इसकी उम्दा मिसाल है—बांगलादेश। इरशाद अब जनता को धर्म की अफीम खिलाकर सुला देना चाहते हैं। उन्होंने बांगलादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की ठान ली है। बांगलादेश में नब्बे प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, लेकिन राष्ट्रों की नींव धर्मों पर नहीं रखी जाती और इससे सिवाय शासक और उच्च वर्ग के किसी को लाभ नहीं होता। बहरहाल, ऐसे माहौल में खालिदा और हसीना के लिए इरशाद को हटा पाना और मुश्किल हो जायेगा। देखा जाये, तो उनकी असली परीक्षा अब होगी।

—मुकेश कुमार

देश

१ मार्च, १९८८: आज़ादी की लड़ाई को जन-जन तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय कवि सोहन लाल द्विवेदी का कानपुर में निधन। पंजाब में पांच मरे। टिकैत द्वारा ७ मार्च से 'जेल भरो' आंदोलन करने का निर्णय।

२ मार्च: राजीव गांधी की संसद में जैल सिंह को करोड़ों रुपए की पेशकश की जांच की घोषणा।

३ मार्च: पंजाब में आतंकवादियों ने ४० लोगों की हत्याएं कीं। पांच मुख्यग्रंथी रिहा हुए।

५ मार्च: सांसद तारिक अनवर बिहार इंका के नये अध्यक्ष। मणिपुर में रिशांग किशिंग की जगह केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री आरके जयचंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने।

६ मार्च: अकालतख्त के जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े द्वारा 'पूर्ण आज़ादी' लेने का संकल्प।

७ मार्च: लोकदल-अ का जनता पार्टी में विलय।

८ मार्च: गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जसबीर सिंह रोड़े को औपचारिक रूप से अकालतख्त का जत्थेदार चुना गया।

९ मार्च: पंजाब में आतंकवादियों द्वारा १४ लोगों की हत्या। नयी दिल्ली में लोकदल-ब और भाजपा की रैली में कांग्रेस को सत्ता से हटाने का आह्वान।

१० मार्च: महाराष्ट्र के स्वास्थ्यमंत्री भाई सावंत का जे०जे० अस्पताल कांड के कारण इस्तीफा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हरिहर सिंह दिवंगत।

११ मार्च: 'नासा' के भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डा० कुमार कृष्ण सम्मानित। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन के १८२ किसान गिरफ्तार।

१२ मार्च: प्रधानमंत्री व उनके सहयोगियों द्वारा 'दांडी कूच' की स्मृति में 'एकता यात्रा'। रोड़े द्वारा आतंकवादियों से हिंसा रोकने की अपील। बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार समरेश बसु का निधन। संजय मंच का जनता पार्टी में विलय और संजय मंच के जेएन मिश्र अपने साथियों सहित कांग्रेस-इ में शामिल।

१३ मार्च: माकपा नेताओं सहित पंजाब में १० व्यक्तियों को आतंकवादियों ने मारा। रिहंद बांध के जलाशय में एक नौका के डूबने से ३० मरे।

१४ मार्च: आतंकवादियों ने पंजाब में १५ व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा।

१५ मार्च: सात प्रांतों में विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 'भारत बंद' पूर्णतः सफल। ५९वां संविधान विधेयक पास। बर्फ के भारी तूफान में लद्दाख में ४१ जिंदा दफन।

समरेश बसु

अकाल तख्त के नये जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े

अफगान समस्या के मध्यस्थ

इरशाद

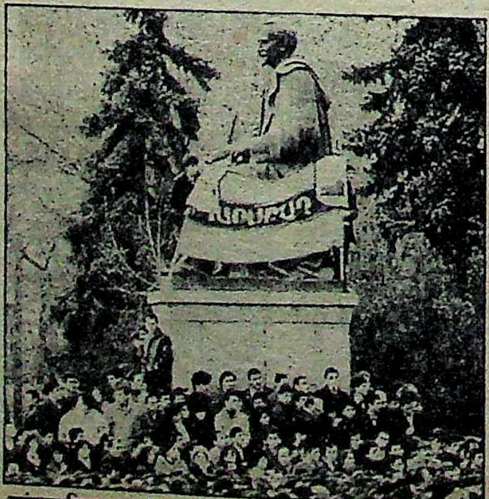

सांप्रदायिक प्रदर्शन

विदेश

१ मार्च: इराक द्वारा तेहरान पर प्रक्षेपास्त्रों से हमला। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग से ४ मरे।

२ मार्च: अफगान समस्या पर जिनेवा में वार्ता आरंभ। साइबेरिया में रूसी विमान गिरने से २० मरे। ईरान-इराक लड़ाई में २६ नागरिक मरे और १०० घायल हुए।

३ मार्च: बंगलादेश में चुनाव के दौरान हुई हिंसा में १४ मरे। श्रीलंका में तमिल मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों ने २१ को मौत के घाट उतारा।

५ मार्च: बंगलादेश के चुनाव में इरशाद की जातीय पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त। पेरिस में विमान दुर्घटना में १९ मरे। सोवियत संघ के जातीय दंगों में ३१ व्यक्तियों की मृत्यु। श्रीलंका में ७ उग्रवादियों सहित ३० मारे गये।

६ मार्च: अमरीकी तटकर अधिकारियों ने पाकिस्तान को भेजी जानेवाली परमाणु सामग्री पकड़ी। श्रीलंका में त्रिकोमाली में बारूदी सुरंग फटने से २२ मरे। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन विरोधी प्रदर्शन के दौरान ९ मरे।

७ मार्च: श्रीलंका के उपगृहमंत्री पर्सी समवीरा ने अपने पद और संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। श्रीलंका में ही १२ तमिल उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

८ मार्च: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्यापक व अनिवार्य प्रतिबंध लगाने की मांग की।

९ मार्च: ईरान और इराक की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी।

१० मार्च: इराक द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव। सुहार्तो इंडोनेशिया के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित।

११ मार्च: वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम हंग का निधन। श्रीलंका में बस रोक कर अज्ञात व्यक्तियों ने १७ लोगों को गोलियों से भूना। ईरान-इराक के बीच लड़ाई रुकी।

१२ मार्च: काठमांडु के स्टेडियम में फुटबाल मैच के दौरान ओलावृष्टि के बाद मची भगदड़ में सौ मरे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फुटबाल-मैच के दौरान हुए हादसे में ३० मरे।

१३ मार्च: इराक द्वारा १,००० ईरानियों को मारने का दावा। ईरान द्वारा रासायनिक हथियारों का निर्माण पुनः आरंभ।

१४ मार्च: ईरान-इराक युद्ध जारी, १६ ईरानी मारे गये। बर्फीले तूफान से पाकिस्तान में २५ मरे।

१५ मार्च: बांगलादेश में तूफान से सौ मरे। श्रीलंका में लिट्टे की महिला सदस्यों सहित २६ मरे। ■

"कुछ नवीन, कुछ अद्भुत्... खेतान ने फिर कमाल किया"

"इसीलिये तो मैं खेतान फैन हूँ"

Hema Malini

– हेमा मालिनी

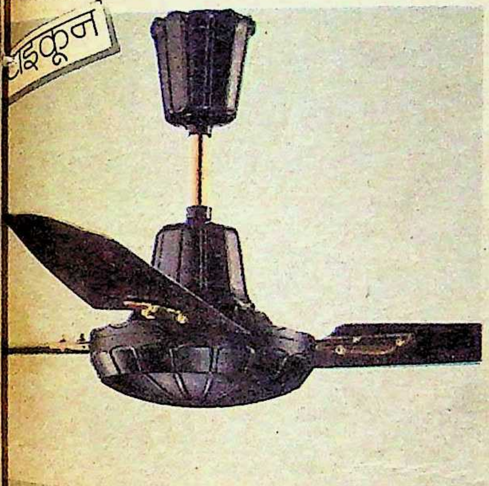

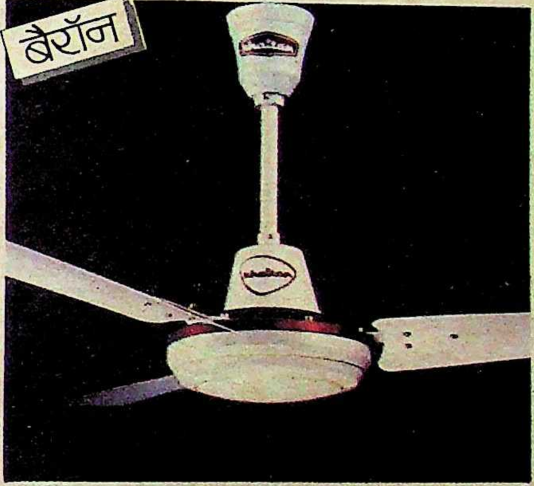

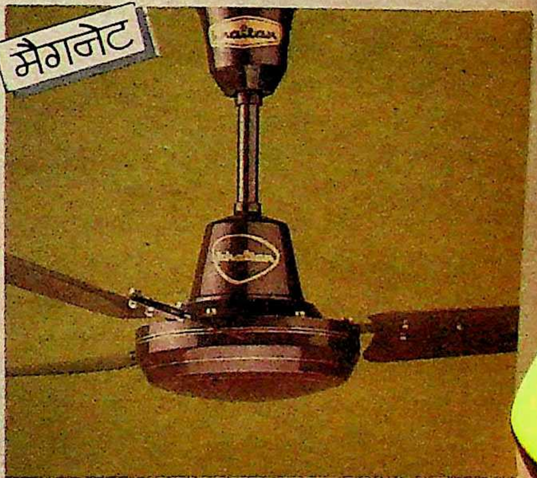

पेश हैं खेतान 3up पंखे

हर कीमत पर क्वालिटी, हर समय अनुसंधान। ये हैं खेतान की जान! खेतान अनुसंधान केन्द्र को भारत सरकार की मान्यता का गौरव प्राप्त है। इस केन्द्र द्वारा बहुत परीक्षणों के पश्चात् एक नई शृंखला के सीलिंग पंखों का निर्माण संभव। वे हैं 'खेतान' 3 up पंखे। समुचित गुण सम्पन्न नये खेतान 3 up पंखों की ३ विशिष्टतायें इस प्रकार हैं:

1up

ज्यादा हवा

नये खेतान 3 Up पंखों में अधिक शक्तिशाली मोटर–अधिक लेमिनेशन, अधिक कापर और अधिक पोल के कारण। नतीजाः काफी ज्यादा हवा–यदि 'खेतान' को देश का सबसे हवादार पंखा कहा जाये तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं।

2up

ज्यादा सक्षम... ज्यादा टिकाऊ

नये खेतान 3 Up पंखों की अनोखी कार्यकुशल मोटर। नतीजाः हर वॉट बिजली खर्च पर मिले अधिक हवा! साथ ही मोटर का तापमान कम रहने से पंखे ज्यादा टिकाऊ।

3up

REPLACEMENT BOND

विश्वास की पराकाष्ठा

नये खेतान 3 Up पखों की उत्कृष्टता एवम् उच्च कार्यक्षमता पर हमारा असीमित विश्वास है। नतीजाः भारत में सर्वप्रथम 'खेतान' द्वारा अनोखी १ वर्ष की 'रिप्लेसमेंट बांड' की सुविधा। अर्थात् किसी भी खेतान 3 Up पंखे में उत्पादकीय त्रुटि मिलने पर पंखा मरम्मत न कर तुरंत बदलने का वादा।

सचमुच घरेलू उपकरणों की दुनिया में एक नया विस्फोट!

आम तौर पर ख़रीदार सूटकेसों में
चार चीज़ें देखते हैं.
लेकिन 'सफ़ारी' देखते हैं ८६ और.

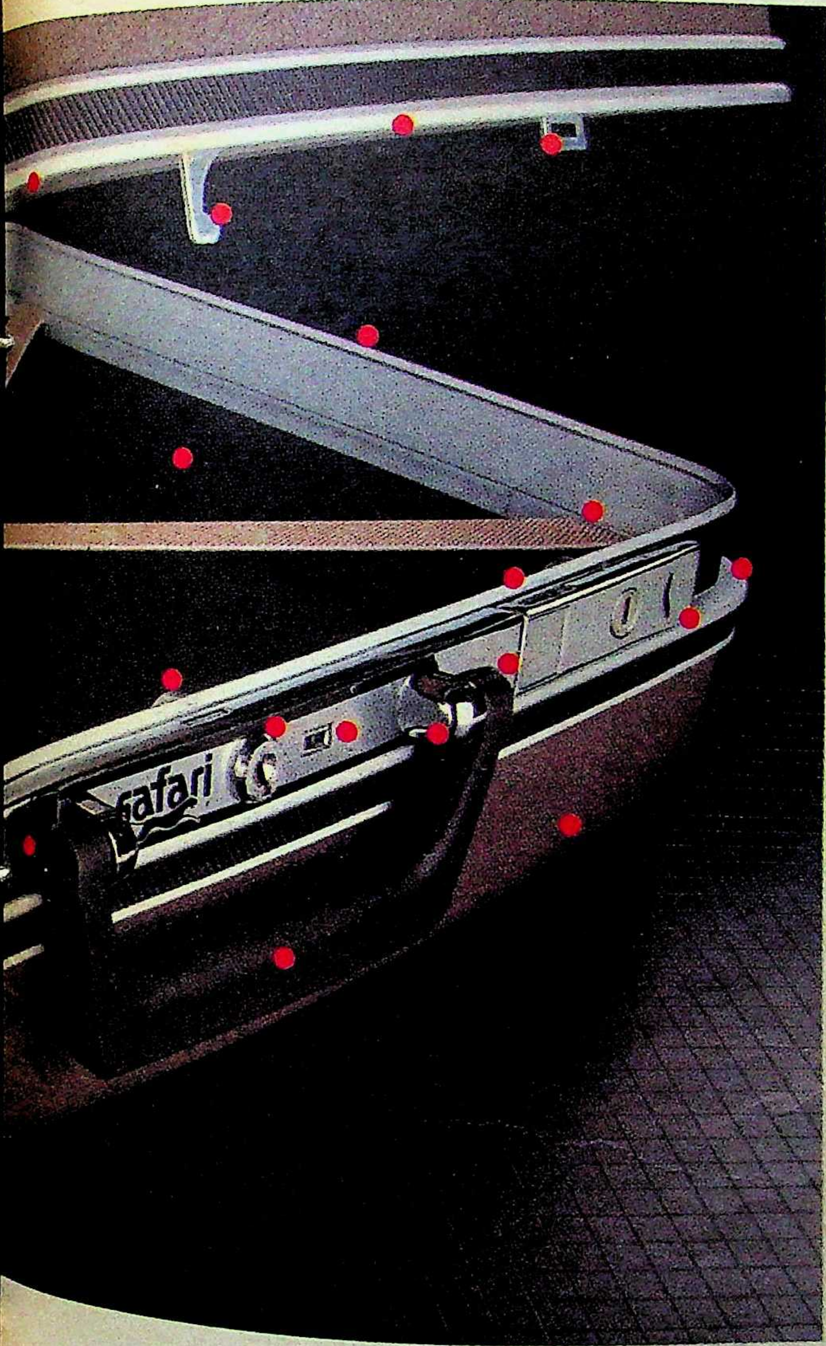

आम तौर पर ख़रीदार सूटकेस लेते समय सिर्फ़ उसका रंगरूप, आकार, साइज़ और क़ीमत ही देखते हैं.

और ख़रीदने के बाद ही जान पाते हैं कि और भी कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें देख लेनी चाहिएं थीं.

लेकिन सफ़ारी खरीदने पर ऐसा नहीं होता.

क्योंकि ख़रीदार के देखने से पहले ही हर सफ़ारी में ९० अलग-अलग बातों की जांच-परख की जा चुकी होती है.

इस बात की तसल्ली के लिए कि आपके सफ़ारी में किसी तरह की ख़ामी न रह जाए.

लेकिन क्वालिटी का मतलब सिर्फ़ जांच करना ही नहीं है. सूटकेस का टिकाऊ होना और उसमें सुविधाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है.

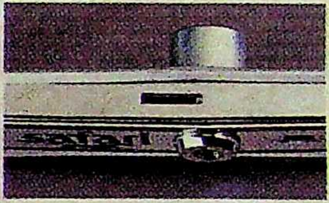

जैसे तालों को ही लीजिए, हर सफ़ारी का बीचवाला ताला ६ लीवर का वॉल्ट-ताला होता है जो कि दूसरे सूटकेसों में इस्तेमाल होनेवाले ४ लीवर या ५ लीवर के मामूली तालों से, १० गुना ज़्यादा मज़बूत होता है.

या फिर कब्ज़ों को बारीकी से देखिए. सफ़ारी के कब्ज़े क्रोमियम प्लेटेड होते हैं लिहाज़ा उनमें जंग नहीं लगता और वे ज़्यादा चलते हैं जबकि दूसरे सूटकेसों में ये ज़िंक-प्लेटेड होते हैं. ऐसी कितनी ही छोटी-छोटी बातें हैं और ये सब एक ही बात साबित करती हैं.

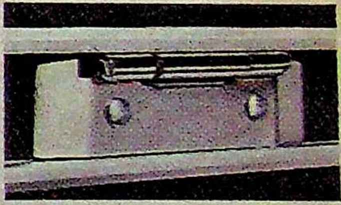

सारी परेशानियां हम उठा लेते हैं ताकि आप परेशान न हों.

safari

भरी हैं इसमें सैंकड़ों खूबियां.

अप्रैल प्रथम '८८

मनोरमा

मूल्य रु० ६/-

कला एवं शिल्प विशेषांक

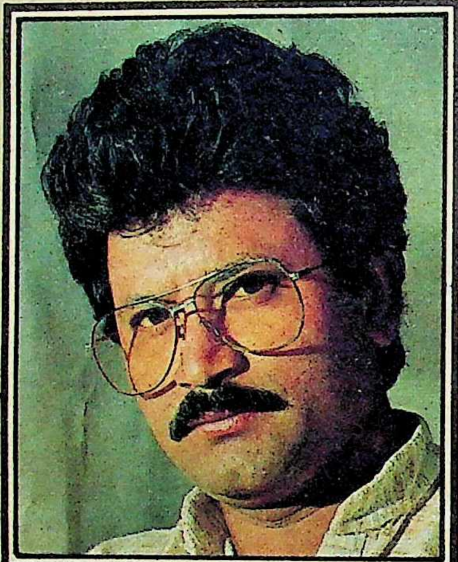

सुरुचिपूर्ण पाठिकाओं को
सुरुचिपूर्ण उपहार

प्रमुख आकर्षण

सुपरग्राफिक्स :
गृहसज्जा का नया आयाम

एक लोकप्रिय हस्तकला :
टाई एण्ड डाई
नीले कुर्ते पर कढ़े हुए लाल
पैच का कमाल
एक आधुनिक वॉलपीस

इकेबाना :
पुष्प-संयोजन की जापानी विधि
सजावट सूखे फूल-पत्तियों की कोलाज
से बनी वॉल हैंगिंग

मोती के गहने :
शान से पहनें कतरनों से
बना आकर्षक पायदान

स्मॉकिंग से सजा रोम्पर सूट बनाइये
चार कलात्मक वस्तुएं
मोती के फूलों का मनमोहक गुलदस्ता
बैग के दो आकर्षक नमूने

आवरण कथा :

क्या पुरुष
वास्तव में तंगदिल होते हैं ?

महिलाएं पुरुषों पर अक्सर यह इल्जाम लगाती हैं, कि वे तंगदिल होते हैं। यह इल्जाम कितना सही है और कितना गलत ? पढ़िए, इस विषय पर एक रोचक विवेचना।

विशिष्ट लेख

गरमी आई और हुई एलर्जी
देखिए, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ?
आखिर किसके लिए नौकरी करती हैं आप ?
जब झगड़ा हो तो मुस्कराइये
प्यार के भूखे होते हैं पालतू जानवर

अन्य आकर्षण

सौन्दर्य : मौसम गर्मी का और देखभाल पैरों की
मेरी सुहागरात : सुहागरात बनाम परीक्षा का रिहर्सल
व्यंजन : खास इस मौसम के लिए
फिल्म : जयाप्रदा और श्रीदेवी
फैशन : फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता के पसंदीदा परिधान
हास्य व्यंग्य : चक्कर पॉश कॉलोनी का
कथा साहित्य : उर्दू की सशक्त कहानी 'कुछ कहते रहो'

साथ ही सभी स्थाई स्तंभ एवं अन्य ढेरों सामग्री

आई.आर.एस.-1ए उपग्रह के कलपुर्जे

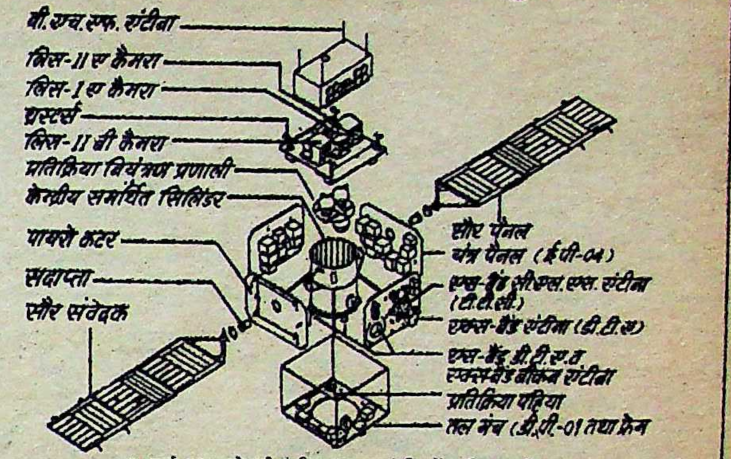
वी.एच.एफ. एंटीना
लिस-II ए कैमरा
लिस-I ए कैमरा
थ्रस्टर्स
लिस-II बी कैमरा
प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली
केन्द्रीय समर्थित सिलिंडर
पायरो कटर
सक्रियता
सौर संवेदक
सौर पैनल
यंत्र पैनल (ई.पी.-04)
एस-बैंड सीएस.एस. एंटीना (टी.टी.सी.)
एक्स-बैंड एंटीना (डी.टी.ए)
एस-बैंड डी.टी.ए.व एक्स-बैंड ग्लोबल एंटीना
प्रतिक्रिया पहिया
तल मंच (ई.पी.-01 तथा फ्रेम

१७ मार्च, १९८८ को रूसी अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित भारतीय उपग्रह

भाप इंजिनों को सन २००० तक अलविदा

रेल उपमंत्री महावीर प्रसाद की घोषणा के अनुसार भारत में भाप से चलनेवाले इंजनों को सन् २००० तक अलविदा कह दिया जायेगा। २१वीं सदी में यहां सभी रेलगाड़ियां डीजल व बिजली से चलेंगी।

पूरे देश में ९४ हजार सरकारी विद्यालय खुले आसमान के नीचे चलते हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या १ लाख, ९२ हजार है, जहां टीन-टप्परों की छत तो है, लेकिन ढंग का फर्श या बिछाने के लिए दरी तक का इंतजाम नहीं है।

बिना इमारतवाले सरकारी स्कूलों की संख्या बिहार में १८३२६, आंध्र में ११७७१ और उत्तर प्रदेश में ११३१९ है।

ऐसे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संख्या ३३ है जो सरकारी भवनों में रहे, लेकिन किराया चुकाये बिना वहां से चले गये। जिन पर दस हजार रुपए से अधिक किराया बाकी है, वे हैं, ए०पी शर्मा (रु० ३६५००.२७), कल्पनाथ राय (रु० २३३०४.१६), अब्दुल गनी खान चौधरी (रु० १७१४६.१५), आर० मल्लिकार्जुन (रु० १२०८६.२५)

भारत में जन्म लेनेवाले प्रति एक हजार बच्चों में ९६ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं।

ब्रह्मांड के संबंध में हुई नयी खोजों के अनुसार ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं और असंख्य महाकाय बुलबुलों के आकार के महाशून्यों की शृंखला से बना है। एक बुलबुला करीब एक करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है और एक आकाशगंगा में १० अरब से अधिक सितारे (सूर्य) हैं। एक आकाशगंगा औसतन ६०००० प्रकाश वर्ष लंबी है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में २९७ हजार किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से तय करता है।

वर्ष १९८७ के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में हुई हड़ताल और तालाबंदी के कारण ८४.६६ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महामूर्ख सम्मेलन ने वर्ष १९८८ को 'मूर्ख वर्ष' घोषित किया है, जबकि राष्ट्रसंघ ने इसे अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया है।

जून, १९८७ से ११ फरवरी, १९८८ तक पूरे देश में ४४४ रेल दुर्घटनाएं हुईं।

३८ देशों के ११२ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।

हेमामालिनी, श्रीदेवी, जयाप्रदा, रति अग्निहोत्री, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया सहित ६७ फिल्म कलाकारों पर एक लाख या इससे अधिक आयकर बकाया है।

तमिलनाडु में गत वर्ष श्रीलंका से आये शरणार्थियों की संख्या एक लाख, दस हजार थी, जिनमें से अभी तक सिर्फ ४३४५ शरणार्थी ही वापस गये हैं।

राजकोट जिले के भलिया तालुका में कुंतासी ग्राम के समीप खुदाई में चार हजार वर्ष पुराने एक व्यापार केंद्र का पता चला है, जिसका सागर मार्ग से विदेशों से भी संपर्क था।

सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बंबई सबसे आगे है। बंबई में १९८५ व १९८६ में क्रमशः २६७५९ व २७११६ सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जबकि इन वर्षों में दिल्ली में क्रमशः ६२५४ व ६४५७, कलकत्ता में ८१०८ व ६८११ बंगलोर में ४८०५ व ५१४८ और मद्रास में ५१५५ व ५१३८ सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

भारत सरकार 'आयकर' देने योग्य लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वित्त राज्यमंत्री अजीत पांजा का कहना है कि देश में संपन्न लोगों की संख्या और सकल राष्ट्रीय उत्पादन को देखते हुए आयकरदाताओं की संख्या बहुत कम है। १९८७-८८ के दौरान ३१ जनवरी तक सरकार ने चार लाख, नौ हज़ार नये आयकरदाताओं का पता लगाकर उनसे आयकर के रूप में २६.१६ करोड़ रुपए वसूले।

१९८७ में केंद्रीय फिल्म प्रभाग बोर्ड ने ८०६ फीचर फिल्मों को प्रदर्शन की अनुमति दी, जिनमें तमिल की सर्वाधिक १६७ फिल्में थीं। दूसरा नंबर तेलुगु फिल्मों (१६३) का है। हिंदी फीचर फिल्मों की संख्या १५० थी।

भारत का सबसे महंगा शहर बंगलोर है। यहां एक रुपए की क्रय-शक्ति मात्रा १२.११ पैसे रह गयी। इस हिसाब से कलकत्तादेश का सबसे सस्ता शहर है, जहां एक रुपए की क्रय-शक्ति सर्वाधिक १३.८७ पैसे है। सस्ते शहरों में दूसरा नंबर अहमदाबाद (१३.५५ पैसे) और महंगे शहरों में दूसरा नंबर बंबई (१२.४७) पैसे) का है।

चालू वर्ष में अभी तक सरकार ने व्यापारियों, लाटरीवालों और ठेकेदारों से छापों में १२४.२५ करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी और आयकर विभाग ने ७७६७ छापे मारे, जबकि गत वर्ष पकड़ी गयी अवैध संपत्ति १००.७० करोड़ थी और छापों की संख्या ७०५४ थी।

अभी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत ही हुई है, लेकिन अभी से देश के १५ राज्यों के ४५३१० गांवों में भीषण जल संकट उपस्थित हो गया है। ये प्रांत हैं—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, प० बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार।

रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत ने बताया कि रामायण सीरियल के कारण रविवार को राजधानी में होनेवाली सरकारी बैठकों में कोई नहीं आता।

राजस्थान के एक इंजीनियर प्रकाश चंद कोठरी ने सर्वप्रचलित ३६० डिग्री मीट्रिक प्रणाली को अपूर्ण साबित करते हुए ६०० डिग्री मीट्रिक प्रणाली की खोज की है। यदि इसे मान्यता मिल गयी, तो पूरी गणितीय दुनिया ही बदल जायेगी। इस नयी प्रणाली में एक मीट्रिक डिग्री सौ मिनट और एक मिनट सौ सेकेंड के बराबर होगा तथा इस गणना को एक कल्प अर्थात् ४३२०० लाख वर्ष तक भी गलत साबित नहीं किया जा सकता।

—संयोजन: विनोद मिश्र

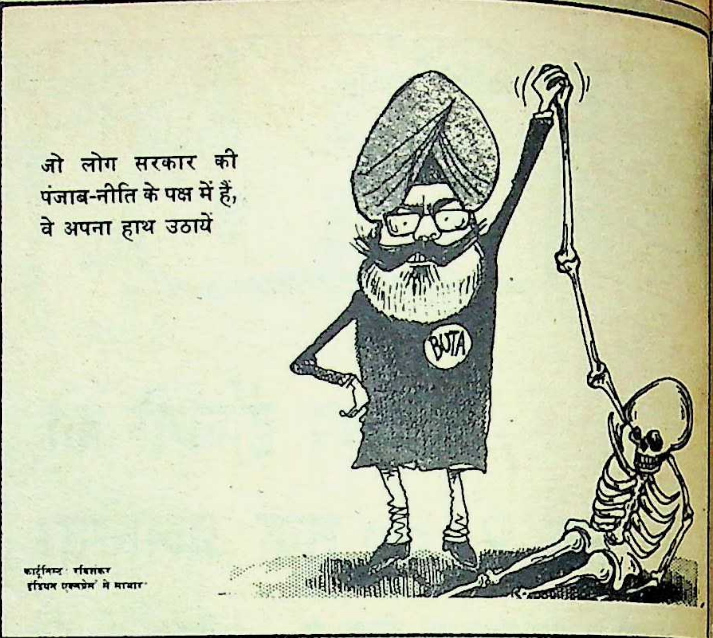
जो लोग सरकार की पंजाब-नीति के पक्ष में हैं, वे अपना हाथ उठायें
BUTA

कार्टूनिस्ट: रविशंकर
'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार

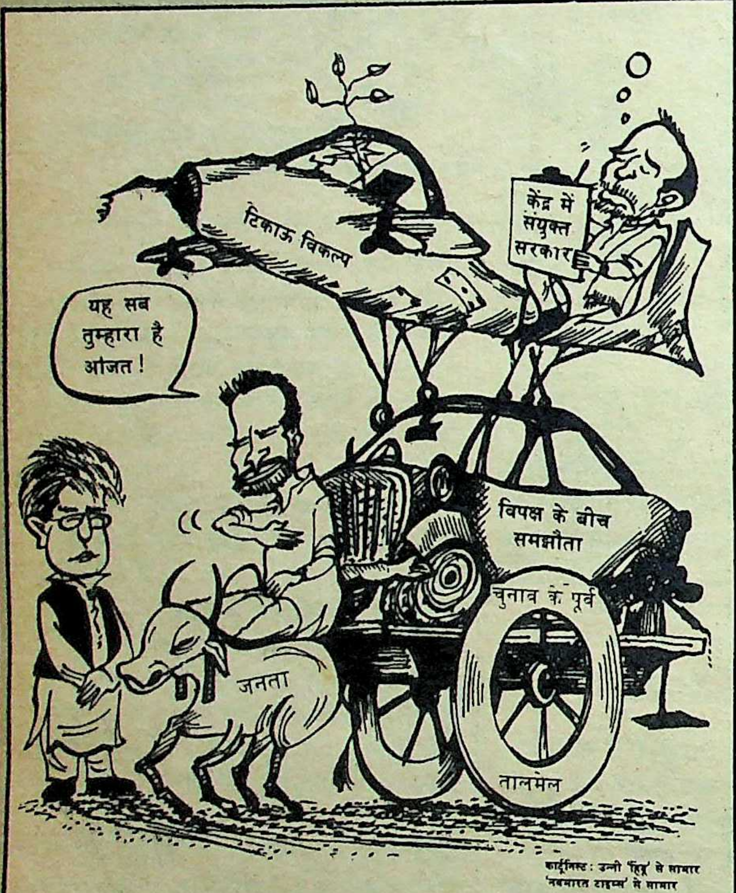
यह सब तुम्हारा है ओजत!
टिकाऊ विकल्प
केंद्र में संयुक्त सरकार
विपक्ष के बीच समझौता
चुनाव के पूर्व
जनता
तालमेल

कार्टूनिस्ट: उन्नी 'हिंदू' से साभार
'नवभारत टाइम्स' से साभार

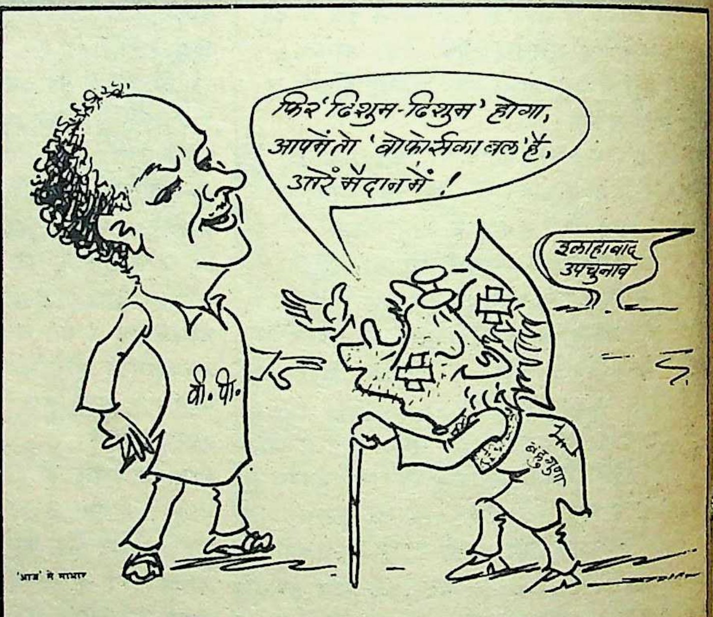
फिर 'ढिशुम-ढिशुम' होगा, आपमें तो 'बोफोर्स का बल' है, आरे मैदान में !
वी.पी.
इलाहाबाद उपचुनाव
बहुगुणा

'आज' से साभार

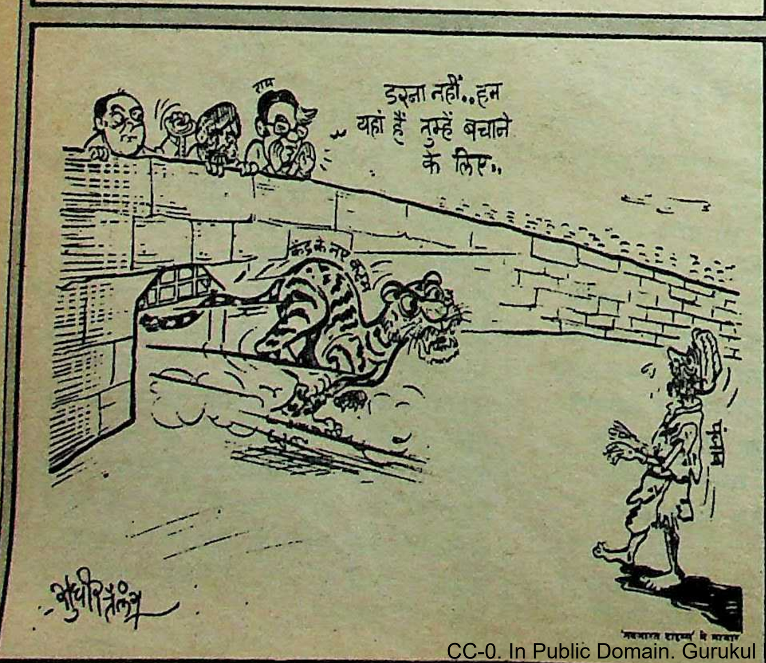
राम
डरना नहीं.. हम यहां हैं तुम्हें बचाने के लिए..
पंजाब
सुधीर तैलंग

'नवभारत टाइम्स' से साभार

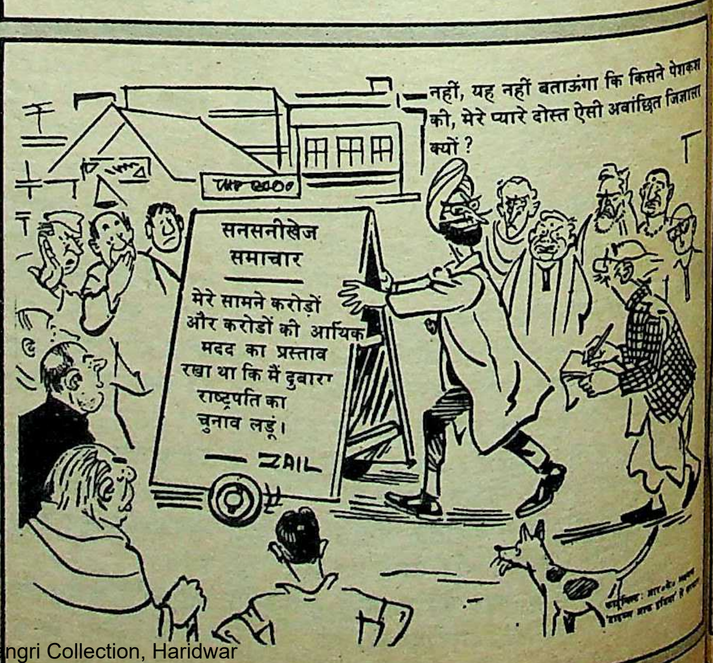
नहीं, यह नहीं बताऊंगा कि किसने पेशकश की, मेरे प्यारे दोस्त ऐसी अवांछित जिज्ञासा क्यों?
सनसनीखेज समाचार
मेरे सामने करोड़ों और करोड़ों की आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा था कि मैं दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं।
— ZAIL

कार्टूनिस्ट: आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

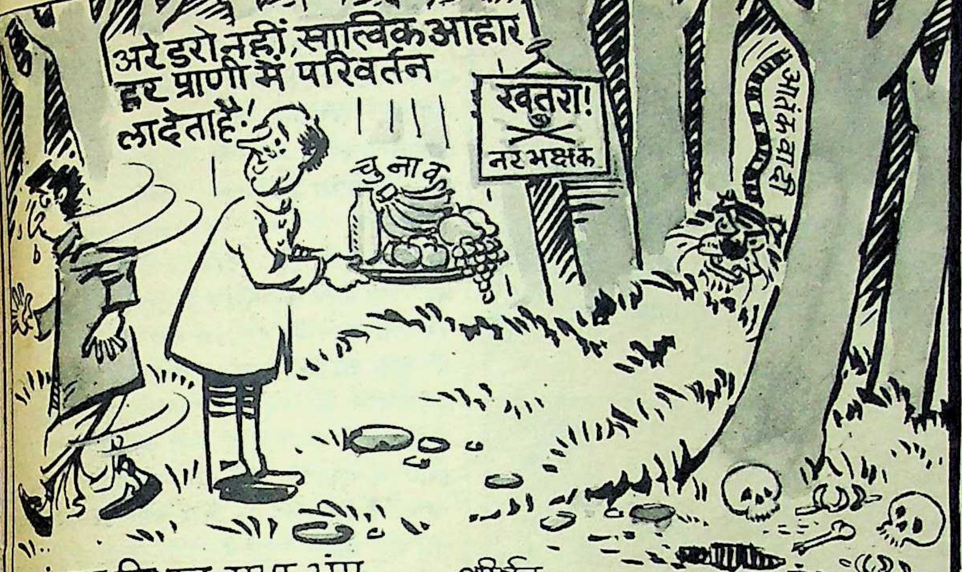
अरे डरो नहीं, सात्विक आहार हर प्राणी में परिवर्तन ला देता है!
खतरा! नर भक्षक
चुनाव
आतंकवादी

पंजाब-विधान सभा भंग — शीर्षक

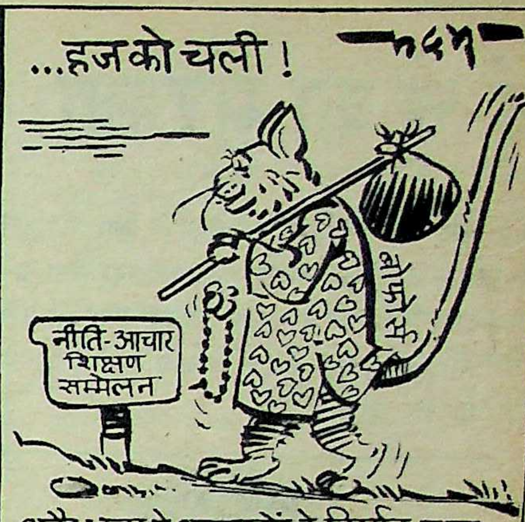
...हज को चली !
नीति-आचार शिक्षण सम्मेलन
बोफोर्स

अवैध रूप से शस्त्रास्त्रों के निर्यात तथा भारत-बोफोर्स कांड से हुई बदनामी को बोफोर्स धोने के प्रयास में —

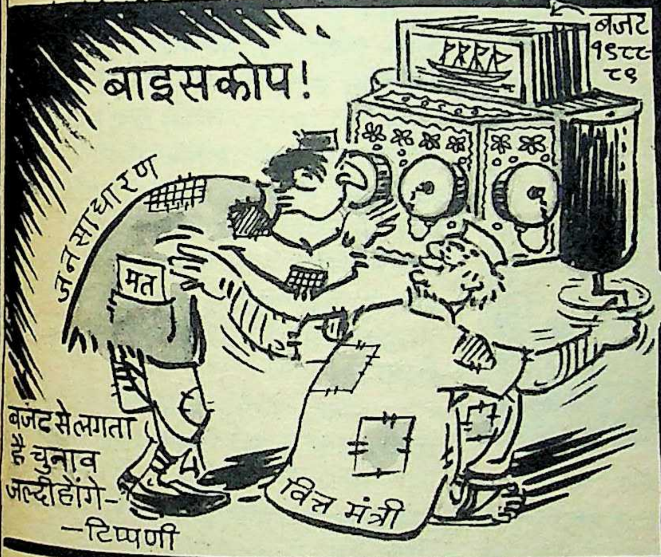
बाइसकोप!
बजट १९८८-८९
जनसाधारण
मत
वित्त मंत्री

बजट से लगता है चुनाव जल्दी होंगे-
—टिप्पणी

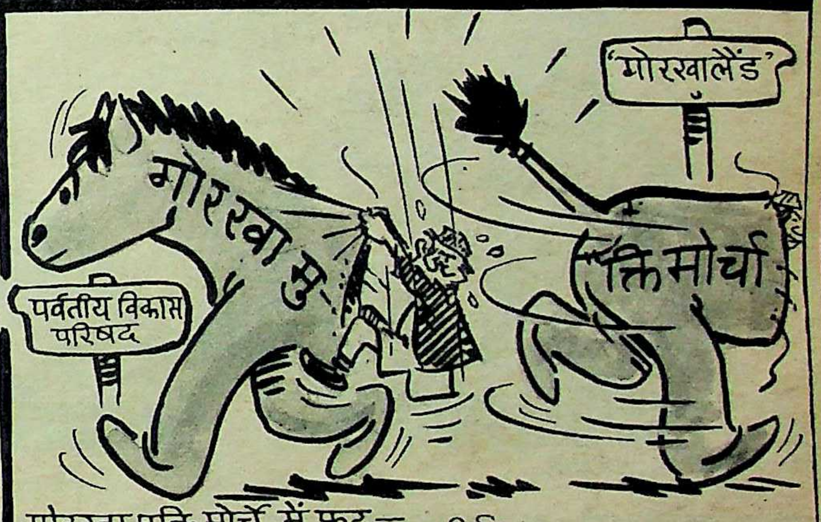
'गोरखालैंड'
गोरखा मु
क्ति मोर्चा
पर्वतीय विकास परिषद

गोरखा मुक्ति मोर्चे में फूट — शीर्षक

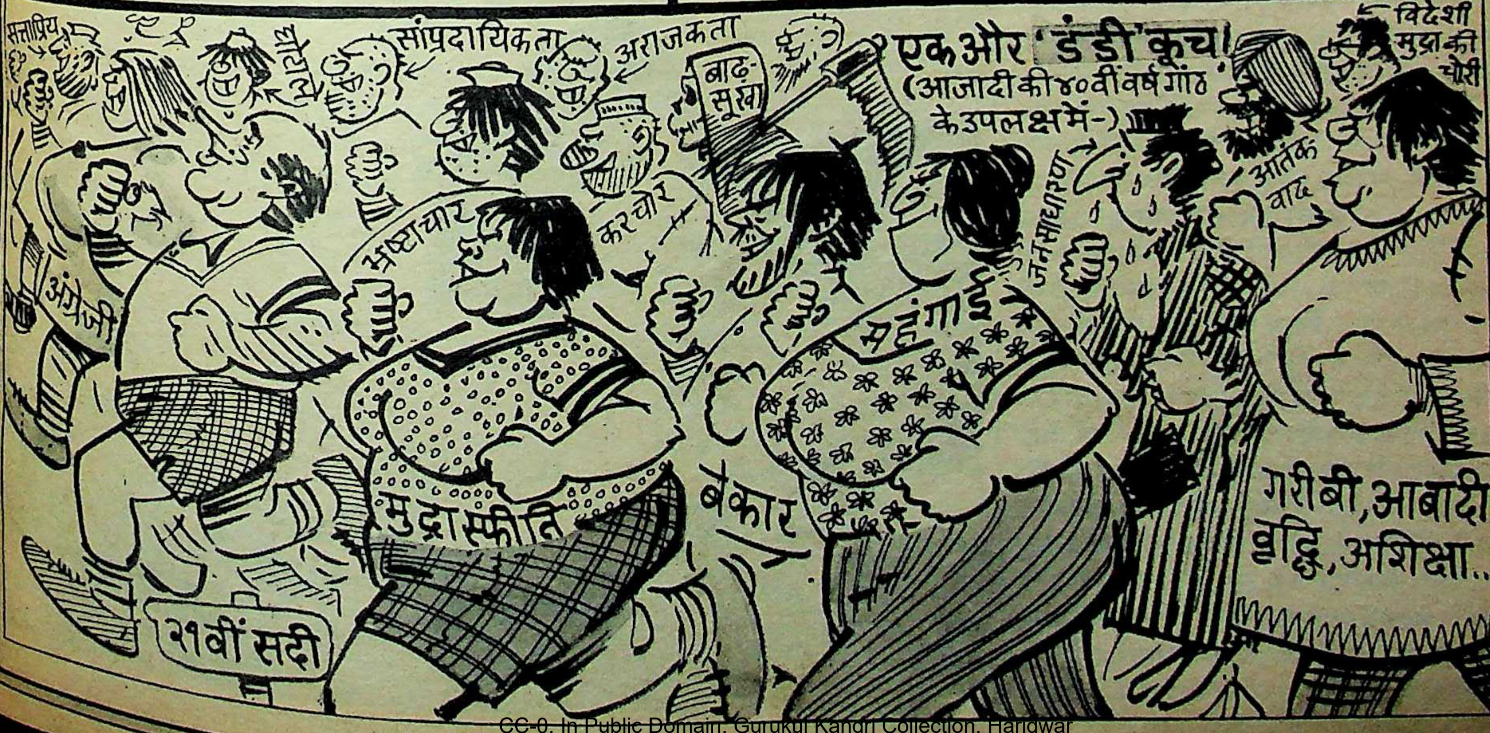
सत्ताप्रिय
घोटाले
सांप्रदायिकता
अराजकता
बाढ़ सूखा
एक और 'डंडी' कूच!
(आजादी की ४०वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में-)
विदेशी मुद्रा की चोरी
आतंकवाद
जनसाधारण
भ्रष्टाचार
करचोर
अंग्रेजी
महंगाई
मुद्रास्फीति
बेकार
गरीबी, आबादी वृद्धि, अशिक्षा..
२१वीं सदी

आकाशगंगा

चूं-चूं का मुरब्बा

यों तो छोटे परदे की फिल्मों को चुनने के लिए मंडी हाउस की काफी आलोचना हो चुकी है, फिर भी उसने न जाने क्या समझकर 'आकाश गंगा' जैसा ऊबाऊ सीरियल चुना। कमलेश्वर जैसे मशहूर लेखक द्वारा लिखे जाने के कारण 'आकाश गंगा' को मंडी हाउस ने हरी झंडी दिखायी या कुछ और कारण थे। आखिर ऐसा क्या है 'आकाश गंगा' में कि उसमें काम करने वाले पात्र भी उसकी आलोचना कर रहे हैं?

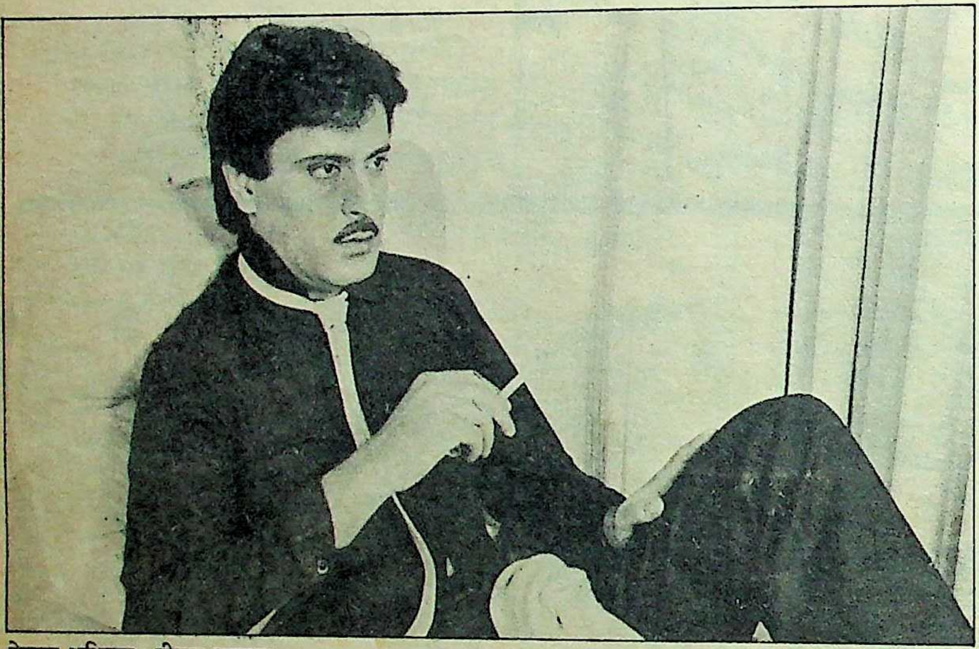

बेजान अभिनय : दीपक पराशर

अगर 'आकाश गंगा' के रचनाकार सुधी कथाकार कमलेश्वर नहीं होते, तो किसी को इतना घटिया सीरियल देखकर आश्चर्य नहीं होता कि १३ एपीसीडों वाले इस सीरियल के सात एपीसोडों को देखने के बावजूद दर्शक यह नहीं समझ पाते कि इस सीरियल की कहानी क्या है और निर्देशिका नीरजा गुलेरी, जो इत्तिफाक से इस सीरियल की वेशभूषा एवं सेट व्यवस्था की भी इंचार्ज हैं, कहना क्या चाहती हैं। दर्शक कभी इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि वे रामसे ब्रदर्स की कोई घटिया हारर फिल्म देख रहे हैं, तो कभी उन्हें लगता है कि वे किसी पुनर्जन्म मार्का भूल-भुलैयावाली फिल्म देख रहे हैं जिसका नाम 'आकाश गंगा' की बजाय 'फ्लैश बैकों की भूलभुलैया' होना चाहिए था और यह इत्तिफाक था कि भीष्म साहनी का १४ वर्षों तक अचर्चित पड़ा रहा उपन्यास 'तमस' सीरियल के माध्यम से जब समूचे दर्शक वर्ग का ध्यान आकंर्षित कर रहा था, ठीक उसी के समापन के साथ-साथ कमलेश्वर का यह सीरियल 'आकाश गंगा' शुरू हुआ जिसका प्रसारण पिछले ढाई-तीन वर्षों से रोके रहने के कारण मंडी हाउस चतुर्दिक आलोचना का पात्र हो रहा था।

मैं कुछ नहीं कहना चाहती : अनीता राज

जिस समय 'आकाश गंगा' का निर्माण हुआ था, उसी समय अगर यह प्रदर्शित होता, तो सभवत सबसे बड़ा स्टार कास्ट एवं भव्य अंत:सज्जावाला निर्जीव सीरियल साबित होता। लेकिन इस दौरान इसके सभी कलाकार (अनीता राज, विद्या सिन्हा, रंजीता, परीक्षित साहनी, दीपक पराशर तथा अनिल धवन) बीते कल की बात हो चुके थे।

घटिया सीरियल : "मैंने यह सीरियल सिर्फ कमलेश्वर के नाम पर साइन किया था।" 'आकाश गंगा' की नायिका अनीता राज का कहना था, "वह बहुत बड़े लेखक हैं, इसलिए उनकी लेखनी पर शक करने की गुंजाइश नहीं थी। फिर हमने यह भी सुना था कि 'आकाश गंगा' पर वह फिल्म भी बनानेवाले थे। रही सीरियल के बारे में बात, तो मुझसे जैसा कहा गया वैसा अभिनय कर दिया। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती।" 'आकाश गंगा' की एक और कलाकार विद्या सिन्हा अब यह मानने लगी हैं कि 'आकाश गंगा' से कहीं लाख दर्जे बेहतरीन था उनका टी०वी० सीरियल 'सिंहासन बत्तीसी' जिसे दूरदर्शनवालों ने बीच में ही 'उतार' लिया था। "अब न तो मैं दूरदर्शनवालों की आलोचना करना चाहती हूं और न ही 'सिंहासन बत्तीसी' की तारीफ। लेकिन जिस तरह के घटिया सीरियल वे सिर्फ सोर्स-सिफारिशों के बल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, वह किसी को कोई अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करता। कमलेश्वरजी के साथ मैं एक फिल्म ('पति, पत्नी और वो') कर चुकी हूं, वह अच्छे लेखक हैं। मैं 'आकाश गंगा' के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती।"

अनीता राज और विद्या सिन्हा 'आकाश गंगा' के बारे में खुलना नहीं चाहती थीं,

ही दूसरे कलाकार, लेकिन उसकी आलोचना करने वे लोग बाज भी नहीं आते कि अगर दूरदर्शन ऐसे ही सीरियल प्रदर्शित करने पर आमादा रहा, तो एक दिन वह अपनी विश्वसनीयता खो बैठेगा। उसमें से कुछ की समस्या है कि 'आकाश गंगा' को देखने के बाद लोग फोन करते हैं कि इसमें काम क्यों किया?

बंबई और मद्रास में बननेवाली मसाला फिल्में नकली होती हैं, जिंदगी की यथार्थता से उनका कुछ भी लेना-देना नहीं होता। इसीलिए बहुसितारीय 'आकाश गंगा' के सारे किरदार ही नहीं, घटनाक्रम, माहौल—सभी कुछ नकली लगता है। प्रासादों को भी मात देने वाले मकानों में बाबा आदम के जमाने के घटिया फोन तथा दूसरे सामान नकली माहौल उपजाते हैं। एक भी घटना या प्रकरण मन को छू पाने में असमर्थ है। और-तो-और 'आकाश गंगा' का थीम सांग 'यह जीवन है आकाश गंगा' की धुन बी०आर० चोपड़ा की फिल्म 'गुमराह' से 'न दिल छुपा के जियो' और समापन गीत 'दिल के दीपक जल कैसा इनसान भी है...' एक दूसरी फिल्म के गीत की धुन से हूबहू ले ली गयी है। सावन कुमार ने उसी मीटर पर थीम के 'बोल' (इसे गीत नहीं, फिल्मी भाषा में प्रचलित शब्द 'बोल' ही कहना चाहिए) लिख दिये।

कमलेश्वर पहले 'आकाश गंगा' पर फिल्म बनाना चाहते थे। शायद फिल्म में यह सारा मेलोड्रामा—अतिनाटकीयता, अयथार्थता और नकलीपन चल जाता, लेकिन जिस अवधारणा को लेकर मंडी हाउस ने सीरियलों के निर्माण और प्रसारण की बुनियाद रखी थी, उसकी कसौटी पर 'आकाश गंगा' बंबइया फिल्मी मसालों का सिर्फ ऊबड़-खाबड़पन संयोजन भर साबित हुआ। हास्य अभिनेता राजेंद्रनाथ अपने पुराने फिल्मी मार्का अभिनय में उछलकूद करते हैं और 'मैं आदमी नहीं, मैनेजर हूं,' 'आपके कमरे में नहीं भेजा, हम भेजा ब्रेकफास्ट में नहीं भेजा,' 'पांच नंबरजी, यस सरजी' जैसे घटिया, चलाऊ संवाद बोलते हैं और कार के विंड स्क्रीन पर लगे वाइपर जैसा वाइपर युक्त चश्मा पहनते हैं। नौकर हर फिल्मों में दुहराया गया संवाद 'चाय लाऊं मुनुआ?' या दीपक पराशर 'वक्त साथ नहीं दे रहा, इसलिए दूर जा रहा हूं। वापस लौट कर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना स्वाती...' जैसे संवादों का सहारा लेते हैं। इतने बड़े कुबेरपति के मकान में सिर्फ एक नौकर भर है, जो मालिक के सामने कूड़े-कचरे से भरी डस्टबिन लेकर (इसलिए) आ जाता है ताकि मालिक रवि की निगाह डस्टबिन में पड़ी स्वाती की डायरी पर पड़ सके। अब दर्शक आश्चर्य कर सकते हैं कि जिस स्वाती की हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए रवि कोशिश करता है, उसी की डायरी डस्टबिन में कैसे पहुंच गयी?

कमलेश्वर हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और जागरूकता के समर्थक रहे हैं और समानांतर कहानी का आंदोलन चला चुके हैं जिसके तहत उन्होंने नये रचनाधर्मी कथाकारों की एक फौज तैयार की थी, यह दूसरी बात है कि उनके बंबइया फार्मूला फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करते ही यह आंदोलन और यह फौज गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गयी। तब यह लगा था कि किसी आंदोलन की नींव व आंदोलन से जुड़े लोगों की रचनाधर्मिता सिर्फ सामयिक प्रकाशन (जिसे आम फहम बोली में 'छपास' भी कह सकते हैं) तक ही सीमित रहती है, तो अपनी सारी प्रखरता के बावजूद वह अपना 'स्व' खो बैठती है।

घिसा-पिटा अंदाज: रंजीता

लेकिन कमलेश्वर सशक्त कथाकार के साथ-साथ गुलजार निर्देशित फिल्मों 'आंधी' तथा मौसम जैसी फिल्मों के सशक्त रचनाकार भी थे। लेकिन यहां भी वही हादसा हुआ। उन्होंने गुलजार से हट कर जब बी०आर० चोपड़ा, शक्ति सामंत, सावन कुमार टाक की फिल्मों के साथ-साथ जब स्तरहीन फिल्म निर्माता निर्देशकों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक था, उनके रचनात्मक स्तर का अवमूल्यन शुरू हो गया—गुलजार अपना स्तर बनाये रखने में कामयाब रहे, लेकिन कमलेश्वर जिस तेजी से फिल्म-लेखन के आकाश में चमके थे, उतनी ही तेजी से अवमूल्यन के धुंध में गुम हो गये—फिल्म लेखन में जिस नये आंदोलन का संकेत उन्होंने 'आंधी' और 'मौसम' में दिया था, वह उसी फिल्मी फार्मूला-व्यवस्था के शिकार हो गये।

उनकी इसी ह्रासोन्मुख फिल्मी अवमूल्यन की चरम परिणति है— आकाश गंगा' जिसके संवाद इतने घटिया हैं कि वे चौथी श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों के संवाद लगते हैं, इसका निर्देशन प्रस्तुतीकरण, कथ्य-समूचा परिवेश उसी दर्जे का लगने लगता है, बल्कि इस चौथी श्रेणी के निर्माता भी यह फिकरा कसने से बाज नहीं आते कि 'गनीमत है, हम भले ही बुद्धिजीवी नहीं, लेकिन 'आकाश गंगा' से बेहतरीन फिल्में तो बनाते ही हैं...

'आकाश गंगा' है क्या?: अंग्रेजी हुक्मरानों के जमाने में महाराजा और नवाब सेना के बड़े अफसरों के ओहदों (कर्नल आदि) से सम्मानित हो अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। भव्य राजमहलों को भी मात करने वाले 'आकाश गंगा' के मालिक परीक्षित साहनी ने आकाश गंगा के आधे हिस्से को गेस्ट हाउस (पंचसितारा कमरेनुमा ऐसे गेस्ट हाउस भारत में नहीं मिलते और उसमें टिकनेवाले क्लायंट संपन्न कम सड़क छाप आदमी ज्यादा लगते हैं) बना रखा है और खुद नौसेना में काम करते हैं (उनका पद क्या है और काम क्या करते हैं—यह भी गौरतलब दृश्य है!) उसी आकाश गंगा के मालिक-कमांडर की बहन स्वाती (अनीता राज) तथा इला (रंजीता), एकदम फिल्मी स्टाइल में, गेस्ट हाउस के मैनेजर के० लाल उर्फ कुंजी लाल (राजेंद्रनाथ) की सहायता से गेस्ट हाउस में ठहरनेवाले ग्राहकों की बातचीत उनके अनजाने में टेप कराती हैं और सुनकर लुफ्त उठाती हैं। उसी गेस्ट हाउस में ठहरे रवि दत्त (दीपक पराशर) को फोन पर अनिल धवन उस स्वामी के बारे में रोमांस का क-ख-ग पढ़ाते हैं जिन्हें उन दोनों में से किसी ने देखा नहीं है। (ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं)। अंततः एक-दूसरे से मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर अचानक रवि दत्त संपन्न मकान (उसका मकान देखकर तो ऐसा ही लगता है), व्यवसाय (पता नहीं चलता कि वह करता क्या है—यों दफ्तर भी है, कारोबार भी) छोड़कर कुबेरपति बनने के लिए विदेश चला जाता है और जब वापस लौटता है, तो स्वाती गायब हो चुकी है। फिर उसकी तलाश चलती है और फ्लैश बैक में पूर्व कथाएं उसके जेहन को झकझोरती हैं (यों देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वह सिर्फ मजनुओं की तरह इस कमरे से उस कमरे या घरेलू नौकर तथा कुंजीलाल से बात करने के सिवा कुछ नहीं करता। २० मिनट के सीरियल में ५ मिनट वर्तमान में तथा १५ मिनट फ्लैश बैक के अतीत में गुम हो जाते हैं। रवि जिस स्तरहीन फिल्मी पत्रिका को पढ़ता है, उसमें छपे फिल्म अभिनेत्री अनीता राज के चित्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह घर से भाग कर फिल्म अभिनेत्री अनीता राज बन गयी है। परीक्षित साहनी नेवी कमांडर कम, नौटंकी के पात्र ज्यादा लगते हैं और विद्या सिन्हा बनी-संवरी एक्स्ट्रा, जबकि उसके अकेलेपन को बड़ी खूबसूरती फिल्माकर 'आकाश गंगा' में संवेदनशीलता उभारी जा सकती थी।

'आकाश गंगा' के कार्यकारी निर्माता समीर और निर्देशक नीरजा गुलेरी अगर इसे फिल्म बनाकर पेश करते, तो ज्यादा ठीक रहता, कम-से-कम उसे देखने-न-देखने का निर्णय लेने में दर्शक तो आजाद रहता, रविवार की सुबह खराब करने की कुंठा तो नहीं पालता। यों कई गृहिणियां 'आकाश गंगा' से इसलिए खुश रहीं कि उन्हें इस दौरान रसोई घर में जाने का मौका मिल गया, जो 'अपने पराये' के दौरान उन्हें मिला करता था।

छाया: रणजित घटक

—बंबई ब्यूरो

स्वप्ना और दादा कोंडके

दादा कोंडके : आगे की सोच !

फिल्म के रुपहले परदे पर सेक्स, अश्लीलता और गालियों के द्विअर्थी संवादों को पेशकर बाक्स आफिस फार्मूले के सारे अंकगणित को गलत साबित कर देने वाले दादा कोंडके हिंदी फिल्मों के सुनहरे संसार में जब से आये हैं, झटके-पर-झटके खाते जा रहे हैं! एक महीने में मराठी में फिल्म पूरी कर, सिनेमाहालों में हर फिल्म की स्वर्ण/हीरक जयंती मनाकर दादा कोंडके 'गिनीज बुक' में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। एक जमाने के कोल्हापुरी बैंड मास्टर दादा कोंडके से यदि घबड़ाते हैं,तो सिर्फ सेंसर बोर्ड के अफसरान, जिनके पास उनके अश्लील संवादों के अर्थ को काटने का रामबाण नुस्खा तक नहीं होता। वही दादा कोंडके जब 'अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में' जैसे द्विअर्थी अश्लील टाइटिल को भी सेंसर सें पास करा कर तथा सिनेमा हाल में दोनों हाथों पैसे बटोर कर हिसाब-किताब करने बैठे, तो उन्हें लगा कि वह अपनी परमानेंट हीरोइन-जोड़ीदार उषा चह्वाण के कंधे पर रखकर दुनाली हिंदी दर्शकों पर नहीं चला सकते। सो उन्होंने मद्रास से आकर बंबई में धूम मचा रही स्वप्ना का कंधा चुना और अगली फिल्म का नाम रख दिया 'आगे की सोच'। अब इस फिल्म के निर्माण के दौरान उन्होंने सचमुच इतने झटके खाये कि उन्हें आगे की सोचने के लिए बाध्य होना ही पड़ा।

लेकिन स्वप्ना का कहना है, "सिर्फ घुटन्नी निकर पहन और उलटी-सीधी हरकतें कर आगे को नहीं सोचा जा सकता," लेकिन दादा मानते हैं कि आगे की सोचने के लिए अक्ल नहीं चाहिए, क्योंकि दर्शक सिनेमा हाल में घुसते समय अपनी अक्ल जेब में जो रख लेता है!

धर्मेंद्र

छाया : बालकृष्ण

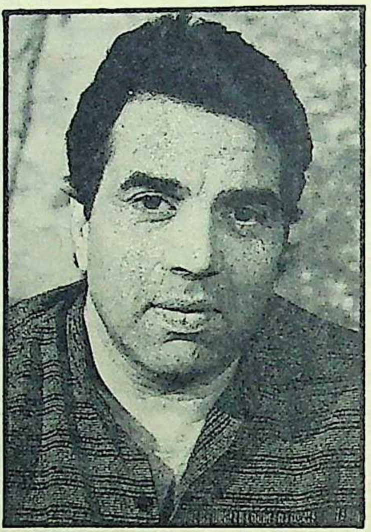

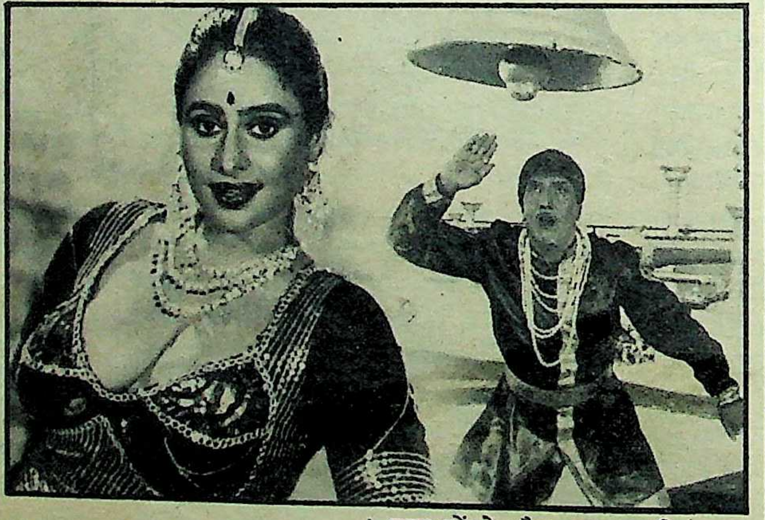

दादा कोंडके और हुमा खान फिल्म 'आग की सोच' में

धर्मेंद्र : जालिम, तुम्हारे हुक्म ने...

'साकी तुम्हारे हुस्न ने कातिल बना दिया' इस मुखड़े के रचयिता का नाम तो धर्मेंद्र भी नहीं जानते, लेकिन इसके दो शब्दों में परिवर्तन कर इसे उन पर मौजूं जरूर बनाया जा सकता है—'जालिम तुम्हारे हुक्म ने शराबी बना दिया!' धर्मेंद्र जब पीना शुरू करते हैं, तो उसका न आदि होता है न अंत! जब वह गुस्से और निराशा के बीच के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें शराब (नीट) और पानी का फर्क ही पता नहीं चलता। इससे उबरते ही वह तौबा कर शराब के पेग की जगह दूध का जग थाम लेते हैं और सारी नैतिकता-अनैतिकता भूल जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके गुस्से और निराशा के आलम की शुरुआत उनके घर से होती है और उनके 'अफेयरों' पर निगाह रखने के लिए एक जासूस उनके साथ नत्थी कर दिया जाता है। सब कुछ जानते हुए भी वह न तो उस जासूस से पीछा छुड़ा पाते हैं और न ही किचन क्वीन की हुक्म-उदूली कर पाते हैं। ऐसे में कहर बरपता है शराब की बोतल और बरजने आये बाहरी लोगों पर!

फरवरी महीने में जब वह एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए जयपुर गये, तो इस बार भी एक लक्ष्मण-जासूस उनके साथ नत्थी कर दिया गया। धर्मेंद्र इस लंबे शूटिंग शिड्यूल में बीवी नं० २ यानी हेमा को साथ रखना चाहते थे, लेकिन 'नत्थी' के पीछे खड़ी हुकूमत के भय से अपने पुराने किरदार के चोले में वापस आ गये। लिहाजा नशे में धुत्त हो शूटिंग-फूटिंग भूलकर पंचसितारा होटल के सुइट में ही, तांडवकर मन की भड़ास निकालने लगे और समझाने गये उस निर्देशक (जेपी दत्ता) तक की लानत-मलामत कर दी जिससे वह भी कभी खौफ खाते थे और इसी खौफ के कारण वह हेमा की बिटिया का जन्मदिन मद्रास में अधूरा छोड़कर जयपुर पहुंच गये थे। धर्म की हालत इतनी बिगड़ गयी कि बंबई से डाक्टर बुलाकर उन्हें धुत्त हालत में ही लाद-फांद कर बंबई वापस भेजना पड़ा। इस सारे मामले में खामोश रही हेमा अगर सौतिया डाह का तांडव शुरू कर दे तो?

दो शेरिफों का दुखड़ा...

पूर्व शेरिफ-सांसद-स्टार सुनील दत्त को उनकी अमृतसर पैदल यात्रा के दौरान लोगों ने पूरी आशा दिलायी थी कि सन '८८ के नोबल पुरस्कार सहित भारत रत्न (और वह भी न सही, तो पद्मविभूषण तो कहीं गया नहीं) का खिताब सिर्फ आपके लिए हीं सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब अलंकरणों की उस लंबी डायरेक्टरी में उनका नाम कहीं नहीं दिखा, तो उन्होंने तुरंत गांधीबाबा का तरीका अपनाया और अपने निर्वाचन-क्षेत्र की पदयात्रा पर निकल पड़े। लेकिन इसका भी फायदा बंबई के हेडमास्टर मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण की तिकड़म से उन्हें नहीं मिला, तो जुलाई '८८ में नागासाकी से हिरोशिमा की पदयात्रा का ऐलान कर दिया— चलो मुसाहिब बच्चुओ, भारत-रत्न यां पद्मविभूषण न सही, तो १९८९ के नोबल पुरस्कार की इंट्री में तुम लंगड़ी तो नहीं मार सकोगे!

और दूसरे शेरिफ-स्टार दिलीप कुमार! वर्षों पहले जब उन्हें पद्मश्री का आफर मिला, तो उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जो अलंकरण उनकी अभिनय शैली की नकल करनेवाले सितारों (राजेंद्र कुमार ऐंड कंपनी) को मिल चुका है, उसे लेकर अपनी तौहीन क्यों करायें? जब अंतुले का राज महाराष्ट्र में हुआ, तो वह उन्हे पद्मविभूषण दिलाने का नेताई वायदा कर उनके साथ 'फोटो' खिचा-खिचाकर खुद स्टार बन गये। फिर दिल्ली दरबार के मुसाहिबों की लंगड़ी से ऐसे चारों खाने चित्त हुए कि न सितारों की छांह उन्हें रास आयी और न ही बिल्डर माफियाओं का साथ। बेचारे दिलीप कुमार फिर वंचित रह गये और समूचे विश्व में सांस्कृतिक क्रांति का अलख जगाने के लिए दलबल सहित निकल पड़े। उनसे तो अच्छे रहे उन्हीं के अभिनय स्कूल के पट्टशिष्य अमित बाबू, जो सांसद भी बन लिये और बोफोर्स कांड के हीरो बन सारे जहान में नाम भी कमा लिये।

अब बेचारे इन दो पूर्व शेरिफों के अभूतपूर्व दुख को कोई क्या जाने, जिन्हें नियमानुसार असली सरकारी 'प्रोग्रामों' में भी शिरकत के लिए नहीं पूछा जाता!

दिलीप कुमार और सुनील दत्त

छाया: एन० प्रसाद

अमला का जलवा

दक्षिण की हीरोइनों का जलवा कुछ ऐसा होता है बंबइया फिल्म निर्माताओं के ऊपर कि वे उसकी तपिश में सारा तन-मन जला बैठने के बावजूद उसकी स्टारडम-लौ पर पतिंगों की तरह मंडराने और अपनी बलि चढ़ाने से बाज नहीं आते। अमला को हिंदी फिल्मों में आये जुम्मा-जुम्मा कुछ दिन ही हुए कि उसने अपने जौहर दिखलाने शुरू कर दिये। उसकी 'पुष्पक' ने बाक्स आफिस पर सफलता क्या पायी कि फिल्म निर्माताओं की मधुमक्खीनुमा भीड़ उसके दरवाजे के चौखटे पर मत्था टेकने के लिए पिल पड़ी। 'पुष्पक' के बनने फिर उसके प्रदर्शन के पहले अमला ने बंबई के कई चक्कर लगाये, पंच सितारा होटलों में शानदार पार्टियां देकर फिल्म ब्रोकरों को जुटाने की कोशिश की और जब निराश वापस लौटने की सोच रही थी, तो निर्माता-निर्देशक सुरेंद्र मोहन तथा राजेंद्र कुमार उसकी सहायता के लिए आगे आये और उसे अपनी फिल्मों में साइन कर कुछ उसका और कुछ अपनी डूबती नैया को भंवर से उबारने के लिए ताबड़तोड़ फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। अमला ने भी अपने इन भाग्य विधाताओं को उनकी मनचाही डेटें दे दीं। लेकिन 'पुष्पक' के हिट होते ही अमला के दिमाग के साथ-साथ जैसे उसकी नजरें भी फिर गयीं।

अमला की दी हुई डेट्स के आधार पर निर्माता-निर्देशक सुरेंद्र मोहन २० दिनों की शूटिंग शिड्यूल बनाकर मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लों सहित सारा लाव-लश्कर लेकर कश्मीर की बर्फानी वादियों में पहुंच गये, दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार ने होनहार पुत्र कुमार गौरव व गाजेबाजे और यूनिट की फौज के साथ ऊटी में धूनी रमायी, लेकिन अमला अपने इन दोनों 'इंट्रोड्यूसरों' को इंतजार करने के लिए छोड़ कर उस के०सी० बोकाड़िया की टी० रामाराव निर्देशित फिल्म 'कब तक चुप रहूंगी' की शूटिंग में पहुंच गयी, जो कभी उसे घास डालना भी हिकारत की बात समझते थे। बेचारे सुरेंद्र मोहन और राजेंद्र कुमार इस नयी श्रीदेवी—विकल्प की याद में पुराने तर्ज के इस नये गाने को याद कर मन बहला रहे हैं— 'मेरा नाम है बाबू अमला, करती हूं मैं ऐसा हमला...'

—अखबारी लाल

कुमार गौरव और अमला

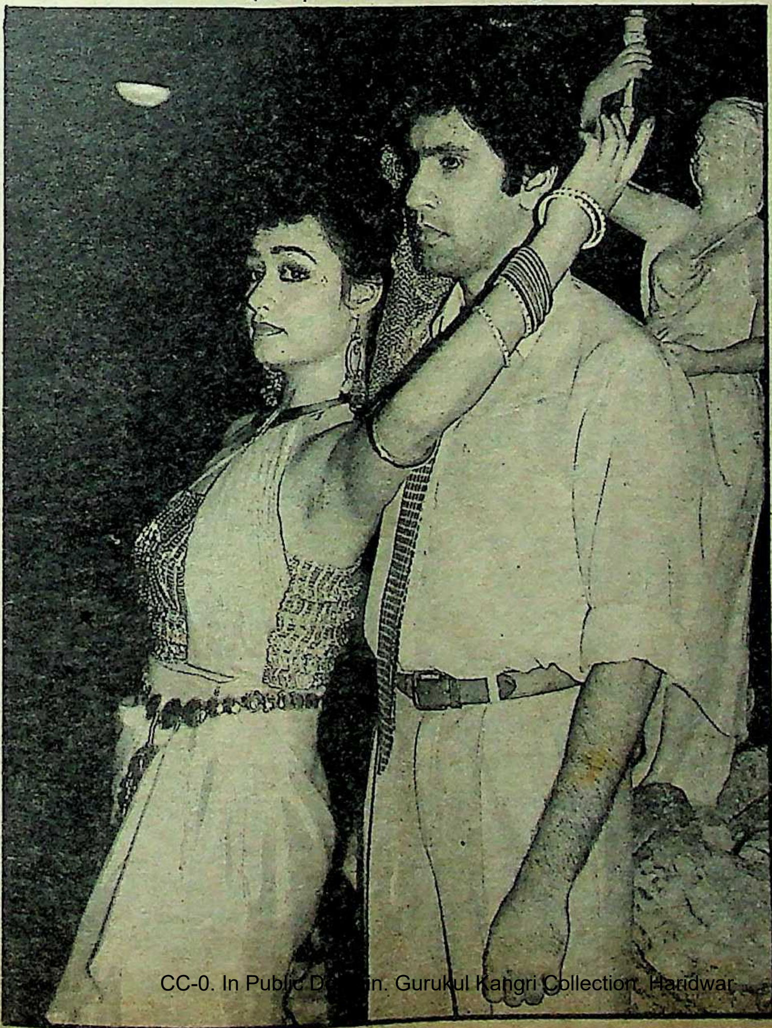

मुरलीधर

दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ भले ही राजनीति और अव्यवस्था के चलते आलोचना का विषय रही हो, पर इस मैराथन दौड़ में जीत हासिल करने वालों की उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता। क्योंकि विजेता धावकों ने भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेकर विजेता होने का संकल्प कर लिया है। जहां दिल्ली मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर आने का श्रेय मुरलीधर को मिला, वहीं महिला वर्ग में आशा अग्रवाल ने यह खिताब हासिल किया। मुरलीधर ने पूरी दौड़ दो घंटे, २२.६ मिनट में जीती, तो आशा अग्रवाल ने दो घंटे, ४७.३० मिनट में दूरी को पार किया।

वाराणसी से ६० किलोमीटर दूर गोपीगंज के मदनपुर गांव के निवासी मुरलीधर इस उपलब्धि को अपनी धावक जिंदगी का केवल एक चरण मानते हैं। उनकी तो तमन्ना है मई में न्यूयार्क में होनेवाले मैराथन दौड़ में भी जीतने की। बाबा विश्वनाथ (काशी विश्वनाथ मंदिर) को अपना द्रोणाचार्य (गुरु) मानने वाले मुरलीधर का बचपन दौड़ने से ही शुरू हुआ। जब वह प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो प्रतिदिन दो किलोमीटर दौड़ कर स्कूल आते-जाते थे और जब मिडिल कक्षाओं में पढ़ने लगे, तो घर से चार किलोमीटर दूर स्थित मिडिल स्कूल में दौड़कर ही आते-जाते थे। यह विवशता नहीं, लगन थी एक अच्छा धावक बनने की।

मुरलीधर का परिश्रम व लगन समय के साथ रंग लाती रही। १९७७ में दिल्ली में वाईएमसीए मैराथन दौड़ को मुरलीधर ने २ घंटा, १८ मिनट में जीता। यह मुरलीधर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। १९७८ में जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के दौरान मुरलीधर दूसरे स्थान पर रहे। इस उपलब्धि पर भी वह खुश थे, क्योंकि प्रथम स्थान पाने वाले शिवनाथ सिंह उनके आदर्श थे। मुरलीधर ने १९८३ में राष्ट्रीय खेलों में दस हजार मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। १९८५ में त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय खेलों की मैराथन स्पर्धा भी मुरलीधर के नाम है।

तीजन बाई

किसी भी कला या कलाकार का सम्मान उपाधि प्राप्त करना ही नहीं है। कला और कलाकार तो वही है जो अपने प्रदर्शन के बल पर अधिक-से-अधिक लोकप्रियता हासिल करके अपनी प्रतिभा की पहचान कायम करे। ऐसे ही कलाकारों की श्रेणी में एक नाम है, तीजन बाई। वैसे तो तीजन बाई १९ मार्च, १९८८ को पद्मश्री से अलंकृत हो चुकी हैं, पर उनकी कला तो वर्षों से दर्शकों के बीच बार-बार अलंकृत होती रही है। जिन स्थितियों से उबर कर तीजन बाई पंडवानी (संगीत नाटिका) के प्रति समर्पित हैं, वह साक्षी है उनके साधकपन की।

फ्रांस (१९८५) और स्विट्जरलैंड (१९८७) में आयोजित भारत महोत्सव में भाग लेकर उन्होंने न केवल भारतीय कला को विदेशियों के हृदय में स्थान दिलवाया, बल्कि विदेशियों के हृदय में अपना एक अलग स्थान भी बनाया।

पंडवानी एक लोककला है जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अंचलों (भिलाई, दुर्ग और आसपास के इलाके) में काफी लोकप्रिय है। यों तो पंडवानी विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं पर प्रस्तुत की जाने वाली संगीत नाटिका है। पर इसकी खासियत है कि गायक ही अपने हाव-भाव से इसे प्रदर्शित भी करता है। पंडवानी में 'महाभारत' की कथा जोड़ दिये जाने के बाद यह कला केवल समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि और भी लोकप्रियता इसके खाते में दर्ज हो गयी। महाभारत कथा के युद्ध-प्रसंगों को जब पंडवानी में प्रस्तुत किया जाता है, तो सुननेवालों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। प्रस्तुत करने वाली तीजन बाई हो, तो फिर क्या कहने? तीजन बाई के पहले इस कला पर केवल पुरुषों का अधिकार था। यह माना जाता था कि कोई स्त्री महाभारत के पात्रों को मंच पर सजीव नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री सुलभ-लज्जा और मर्यादा उस पर विराम लगा सकती है। इस चुनौती को तीजन बाई ने स्वीकार किया और दिखा दिया कि कला स्त्री-पुरुष में भेद नहीं करती।

केवल चौथी कक्षा तक पढ़ी-लिखी और बहेलिया परिवार की तीजन बाई ने महाभारत को पढ़ा नहीं है, लेकिन अपनी रुचि और लगन से पूरी कथा को याद कर लिया है। तीजन बाई की खूबी है कि वह पात्रों का मनोविज्ञान अच्छी तरह समझती हैं और उसी के अनुकूल वह जिस पात्र का अभिनय करती हैं, वह पात्र सजीव हो उठता है।

वैसे आजकल कहा जा रहा है कि जब से वह विदेशों की यात्रा से लौटी हैं, लाउड अभिनय कर रही हैं जो कि ओवर ऐक्टिंग की सीमा लांघ जा रहा है। पर तीजन बाई इसे नहीं स्वीकारतीं। उनका कहना है कि भूमिका से वह इतना जुड़ जाती हैं कि अहसास ही नहीं होता कि कहां ओवर ऐक्टिंग हो रही है। कुछ भी हो, पर तीजन बाई में प्रतिभा है।

दलाई लामा

तिब्बतियों के धर्मगुरु और बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक नेता दलाई लामा को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता तथा मैत्री के लिए इस वर्ष का प० जर्मनी का लूकास पुरस्कार (२१हजार डालर की राशि) मिला है। ट्यूबिजेन विश्वविद्यालय की ओर से यह पुरस्कार १९७२ से प्रतिवर्ष दिया जाता है।

पिछले वर्ष अमरीकी कांग्रेस में दलाई लामा ने तिब्बत में शांति योजना का जो प्रारूप पेश किया था उससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह एक बार फिर उभर कर सामने आये। दलाई लामा की शांति योजना के पांच सूत्र हैं—पूरे तिब्बत को शांति क्षेत्र में बदला जाये, चीनी अपनी जंनसंख्या की अदला-बदली योजना रद्द करें, तिब्बतियों को उनके मानवाधिकार और जनतांत्रिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तिब्बत में चीन द्वारा आणविक इस्तेमाल पर पाबंदी लगायी जाये और भविष्य में तिब्बत के स्वरूप, चीनी और तिब्बती जनमानस के बीच संबंधों के बारे में बातचीत की शुरुआत की जाये। 'तिब्बत हमारा है' के उद्बोधन से तिब्बतियों का इन दिनों जो प्रदर्शन चल रहा है—वह दलाई लामा के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया है। १९५९ से दलाई लामा भारत में रहकर तिब्बत में चीन के खिलाफ चल रहे विद्रोहों का नियंत्रण करते आ रहे हैं।

१९५९ में तिब्बती क्रांति २० वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की दूसरी बड़ी घटना मानी जाती है। चीनी शिकंजे के बढ़ते दबाव और शोषण के लगातार गहराते संकट के खिलाफ शांतिप्रिय तिब्बती जनता का आक्रोश १० मार्च, १९५९ को फूटा और कई हजार तिब्बतियों ने ल्हासा में 'तिब्बत हमारा है, चीनियों वापस जाओ' का नारा बुलंद किया। बगावत हुई और बगावत को दबाने के लिए चीन ने जितनी बारूद खर्च की, वह अपने आप में एक मिसाल है। हजारों तिब्बती मारे गये, ल्हासा शहर में लाशों का बिछौना बिछ गया और राजमहल पर चीनी सेना ने धावा बोल दिया। उसी की परिणति रही कि दलाई लामा को लगभग एक लाख तिब्बतियों सहित भारत में शरण लेनी पड़ी।

दलाई लामा को भगवान अवलोकितेश्वरा का अवतार माना जाता है। 'दलाई' की पदवी १७वीं शताब्दी से चली आ रही है। मंगोलियाई भाषा में 'दलाई' का अर्थ है—सागर और 'लामा' पुजारी को कहते हैं। तिब्बतियों की दलाई लामा में अटूट आस्था है और उनका यह विश्वास अदम्य है कि एक दिन वह तिब्बत जायेंगे, क्योंकि तिब्बत उनका है।

—दिनेश

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,

DUPLIC

20|5|784

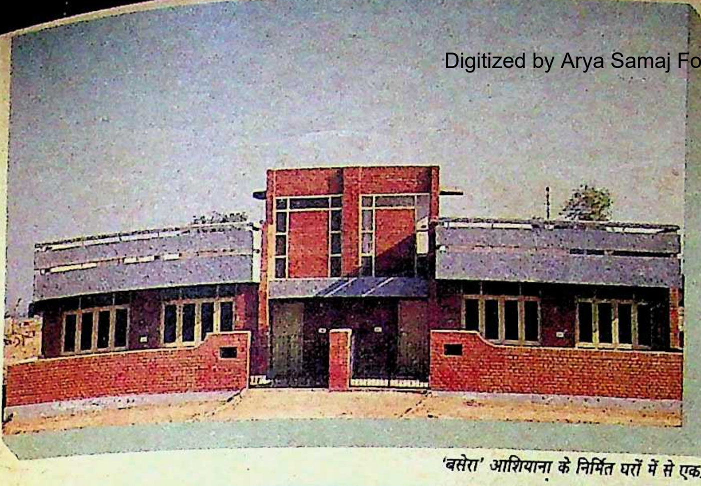
'बसेरा' आशियाना के निर्मित घरों में से एक.

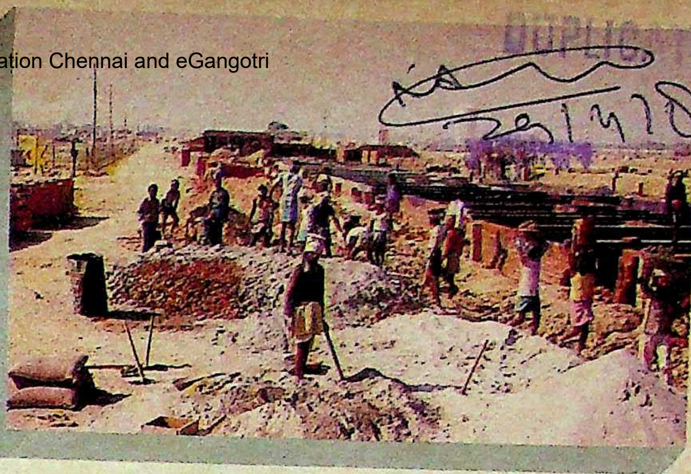
300 घरों का निर्माण प्रगति पर.

आशियाना का अत्याधुनिक व्यावसायिक परिसर–'खज़ाना'

'आरज़ू' – छोटे परिवार का आदर्श घर.

एक खूबसूरत लघुनगर जिसमें है, हर पसन्द हर ज़रुरत के लिए घर.

अन्सल्स

आशियाना

लखनऊ

आशियाना. यही है वह लघुनगर जिसमें आपके सपनों का घर भी है. एक सम्पूर्ण साकार रुप में. ठीक आपकी ज़रुरत के अनुसार, आपकी आर्थिक क्षमता के अनुसार.

आपके चुनाव के लिए है विभिन्न प्रकार के निर्मित घर. शान-ए- अवध, गुलशन और एक्सपैन्डेबल होम्स (विस्तार योग्य घर)– अन्जुमन, बसेरा और आरज़ू. वे घर जो आपकी आज की ज़रुरतों को पूरा करते हैं और भविष्य की ज़रुरतों के अनुसार नीचे तथा ऊपर 3 मंजिलों तक बढ़ाए जा सकते हैं. हर एक के साथ लॉन और किचन गार्डन, हर घर बेहतरीन निर्माण तकनीक की बेमिसाल तस्वीर. सभी कुछ एक स्वस्थ, हरे-भरे वातावरण के बीच. आइये, और आशियाना के निर्मित घरों को देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि अन्सल्स आपके लिए किस किस्म की जीवन-शैली का निर्माण कर रहे हैं, आशियाना के रूप में. 1990 में आपके स्वागत के लिए, आपके प्रवेश के लिए. इसलिए शीघ्र ही अपना मनपसन्द घर बुक कीजिए और निश्चिंत हो जाइये

- प्लॉटों पर कब्जा 1988 में और निर्मित घरों पर 1989 में, विभिन्न चरणों में.
- तेज़ी से विकसित हो रहा है– 10 नमूने के घर तैयार, 300 घरों का निर्माण पूर्णता की ओर.
- 500 एकड़ पर 20,000 परिवारों के लिए लघुनगर.
- हज़रतगंज से मात्र 7 किमी, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टेण्ड समीप ही.
- 5 प्रकार के निर्मित घर तथा 6 आकार में प्लॉट उपलब्ध.
- आधुनिक सुविधाएं-स्कूल, अस्पताल, क्लब, शॉपिंग सेन्टर 'खज़ाना,' पार्क आदि.
- नागरिक सुविधाएं- मल निकास व्यवस्था, जल प्रदाय, बिजली आदि.
- रु. 1.5 लाख तक के आवासीय ऋण भी उपलब्ध.
- सुविधाजनक बुकिंग राशि–शेष आसाना ब्याज़ मुक्त किस्तों में.

विस्तृत विवरण के लिए सम्पर्क करें, लिखें

अन्सल हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड लीज़िंग कं० लि०

2, चायना बाजार रोड (तुलसी सिनेमा के पीछे) लखनऊ -226001 फोन: 48554.
पंजीकृत कार्यालय: 115, अन्सल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली-110 001. फोन: 331-7015 टेलेक्स: 031-62626 ANSL IN.

SEAL OF ansals DEPENDABILITY

ON-LINE/AHL/FP-2/88

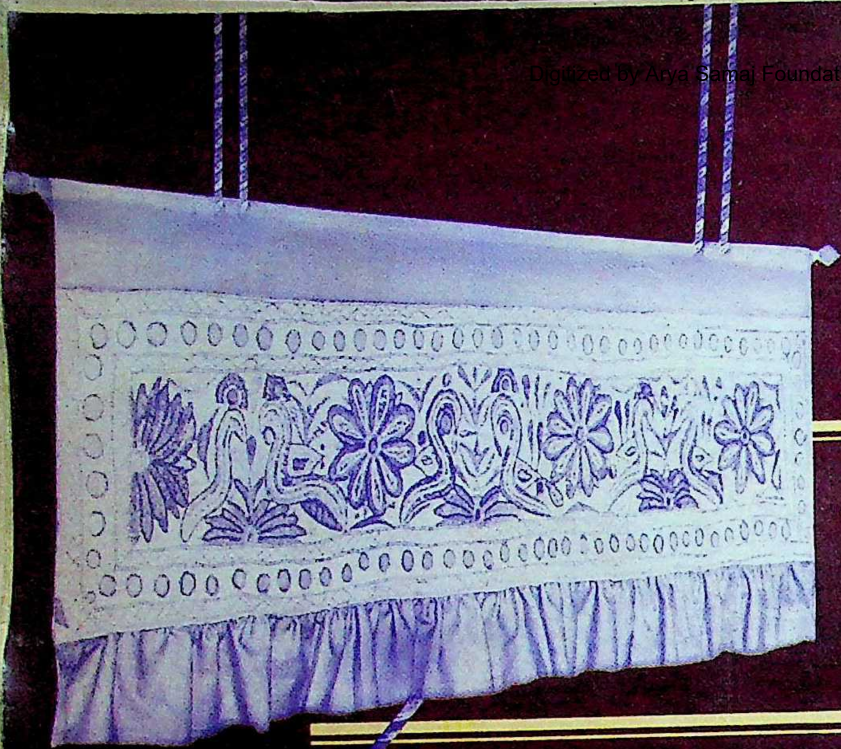

पिछले ५०

रहन-सहन के जित

हम सदा आपके सं

bajaj group

बजाज
स्वर्ण
जयंती
1938-88

0रसों में आपके ीत भी रंग बदले, सं रहे.

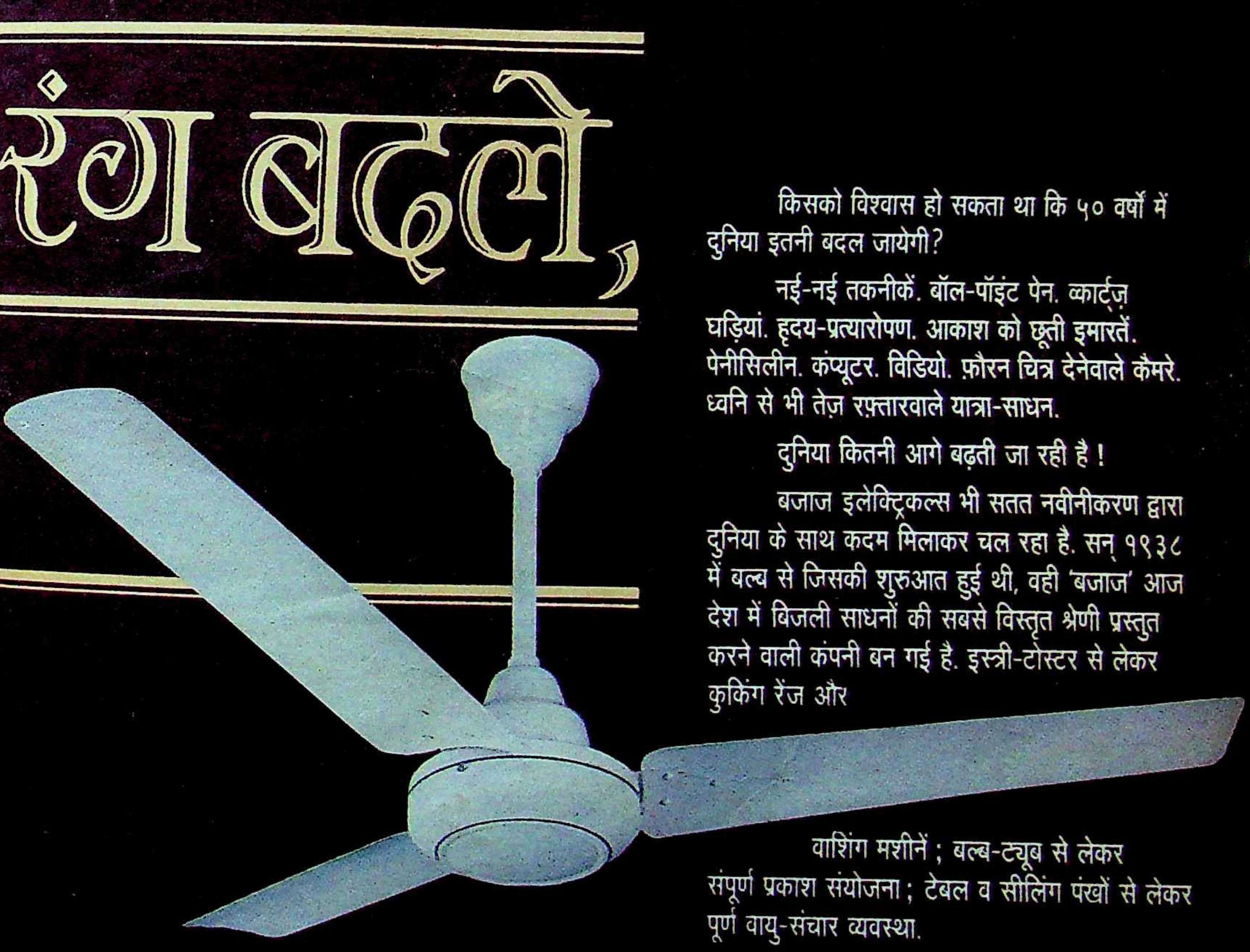

किसको विश्वास हो सकता था कि ५० वर्षों में दुनिया इतनी बदल जायेगी?

नई-नई तकनीकें. बॉल-पॉइंट पेन. क्वार्ट्ज़ घड़ियां. हृदय-प्रत्यारोपण. आकाश को छूती इमारतें. पेनीसिलीन. कंप्यूटर. विडियो. फ़ौरन चित्र देनेवाले कैमरे. ध्वनि से भी तेज़ रफ़्तारवाले यात्रा-साधन.

दुनिया कितनी आगे बढ़ती जा रही है !

बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी सतत नवीनीकरण द्वारा दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल रहा है. सन् १९३८ में बल्ब से जिसकी शुरुआत हुई थी, वही 'बजाज' आज देश में बिजली साधनों की सबसे विस्तृत श्रेणी प्रस्तुत करने वाली कंपनी बन गई है. इस्त्री-टोस्टर से लेकर कुकिंग रेंज और वाशिंग मशीनें ; बल्ब-ट्यूब से लेकर संपूर्ण प्रकाश संयोजना ; टेबल व सीलिंग पंखों से लेकर पूर्ण वायु-संचार व्यवस्था.

लेकिन ५० वर्षों के बाद भी हमने काम करने का कुल एक ही तरीका सीखा है–जो भी करें, बिलकुल साफ़-सही करें. अर्थात एक ऐसी कार्य संस्कृति की रचना जहां साफ़-सुथरी डिज़ाइनें, बढ़िया क्वालिटी के कलपुर्जों का उपयोग, निर्माण की आधुनिक तकनीक, क्वालिटी की सही जांच प्रणाली, और देशभर में २५०० केंद्रों के द्वारा विक्री के पहले व बाद की कुशल सेवा उसके महत्वपूर्ण अंग हैं.

बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

जैसी कथनी वैसी करनी

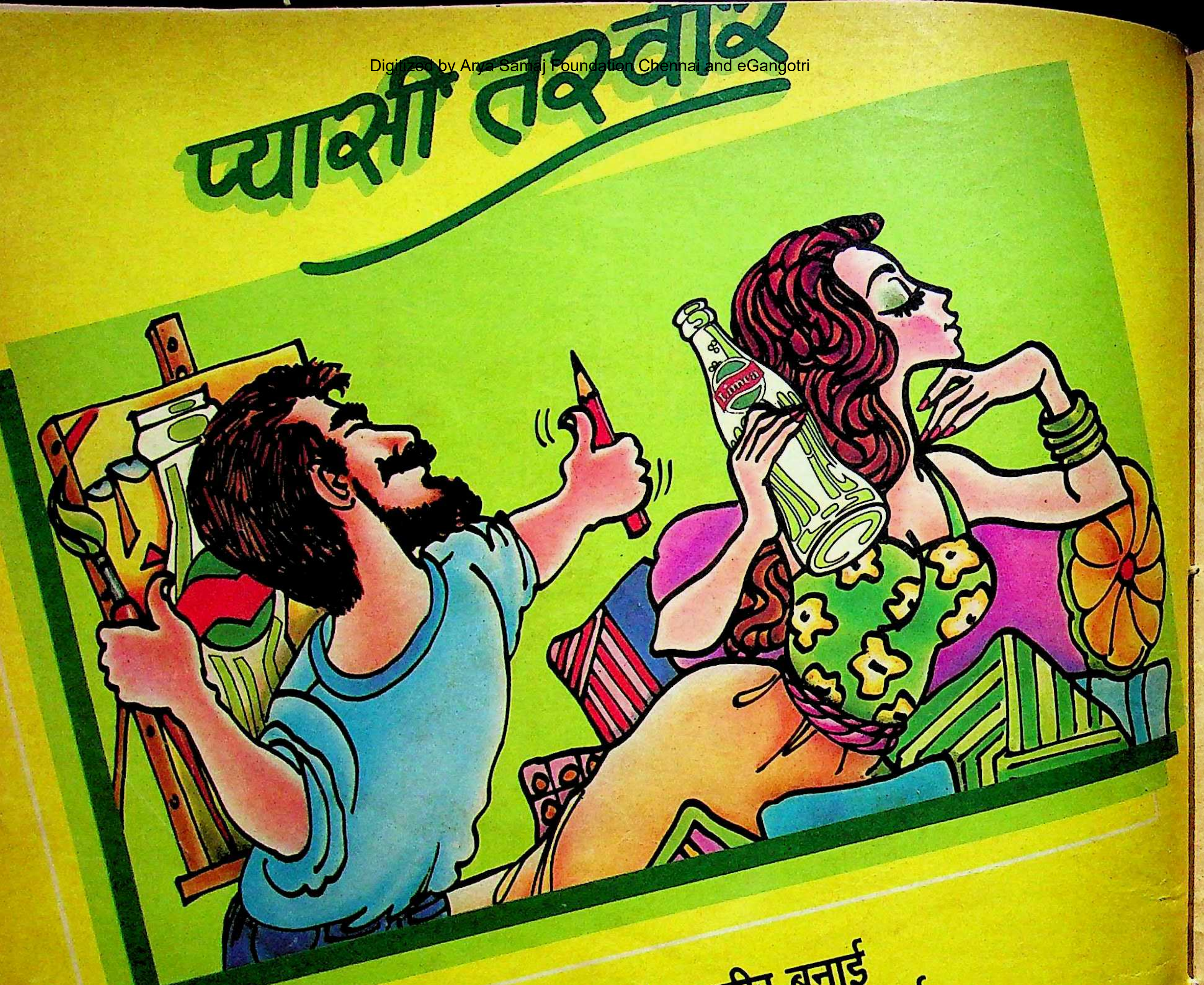
प्यासी तस्वीर
Limca

मेहनत से तस्वीर बनाई
लिम्का पी कर प्यास बुझाई.

जब आप किसी 'शाहकार' की रचना करते-करते या फिर उस शाहकार के लिए 'मॉडल' करते-करते थक कर प्यास से बेहाल हो जायें तब आयसोटॉनिक साल्ट वाले किटाणुरहित लिम्का की बोतल उठायें और अपनी प्यास बुझायें.

Limca®
नींबू जल-सा मज़ेदार पेय
ठंडा बर्फीला पिएं-पिलाएं

RADEUS/PE/L/2-88

Limca
Limca

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

१५ मई, १९८८

वर्ष ५९ अंक ९

माया

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५६६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २६६०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

माया
पंजाब में राज
दिल्ली सरकार या आतंकवादियों का?

१४

आवरण कथा

इस वर्ष के शुरू में केंद्र ने पंजाब में जिस दो सूत्री नयी रणनीति का सूत्रपात किया है, उससे वहां स्थिति और खतरनाक हो गयी है। जिन जसबीर सिंह रोड़े पर केंद्र ने दांव लगाया था, उन्होंने १३ अप्रैल को बैसाखी के दिन अपना असली रंग दिखा दिया है। क्या पंजाब में आतंकवाद की जगह सशस्त्र विद्रोह ने ले ली है? पंजाब के चार जिलों में क्या आतंकवादी समानांतर सरकार चला रहे हैं? सिख, सिख को ही क्यों मार रहा है?

विशेष रिपोर्ट

लोकदल-अ को मिलाने के बाद जनता पार्टी में जो विद्रोह उफना था, क्या वह दब गया है? ३५

अटलबिहारी वाजपेयी

भारतीय विपक्ष में भाजपा की स्थिति और राजीव सरकार के संदर्भ में वाजपेयी का विचारोत्तेजक साक्षात्कार ४०

उत्तर प्रदेश

इंका विधायक कत्याल की कानपुर में हत्या करने के पीछे आतंकवादियों का असली इरादा क्या था? ६४

महाराष्ट्र

हिंदूवादी विचारों के लिए कुख्यात बाल ठाकरे के सिखों के बहिष्कार के आह्वान के खतरे ५३

राजबब्बर

फिल्मों के साथ राजनीति में दखल रखनेवाले राजबब्बर से लीक से हटकर इंटरव्यू: ७३

मध्य प्रदेश

अर्जुन सिंह ने जिस तरह दिल्ली से वोरा की नींद हराम कर रखी थी, क्या अब वोरा ने उनका बदला लेना शुरू कर दिया है? ५९

दिल्ली दरबार: अमिताभ के नाई का नुस्खा ८
खबरों के आगे, खबरों के पीछे १०
तथ्य-कथ्य १२
फोटोफीचर २९
बेढब ३३
देश: भाजपा का आगरा अधिवेशन: पुरानी पहचान बनाने की कोशिश ४४
तमिलनाडु: सत्ता के लिए जंग शुरू ४७
कर्नाटक: आंखफोड़ू आपरेशन ४८
बिहार: तस्वीर की राजनीति ५०
बिहार: एक चक्कूबाज मंत्री ५१
राजस्थान: हरिजन लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ ५६
मध्य प्रदेश: सांसद के कारखाने में दुर्घटना ६०
हरियाणा: तैयब हुसैन ने पाला ऐसे बदला ७०
गुजरात: लतीफ कैसे रिहा हुआ? ७२
अभिमत: स्वामी प्रज्ञानंद: भगवानों से सावधान ७८
विदेश ८०
अर्थतंत्र ८२
धनधंधा ८४
खोजखबर: दवा के नाम पर जहर ८६
दूरदर्शन: पार्वती खान और डा० राही मासूम
रजा से बातचीत ९२
पुस्तक चर्चा: झीनी-झीनी बीनी चदरिया ९४
उपकरण ९७
पाक्षिकी ९८

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया
राजा बनाम शहंशाह

राजा बनाम शहंशाह

'माया' का ताजा अंक (३० अप्रैल, १९८८) देखा। आवरण कथा 'राजा बनाम शहंशाह' अत्यंत रोचक लगी, शैली की दृष्टि से। 'माया' जिसे चाहे उठा दे, जिसे चाहे गिरा दे, इस मामले में उसका कोई सानी नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले 'माया' ने जब चुनाव पर आवरण कथा छापी थी, तो उसमें अमिताभ-ही-अमिताभ थे, जबकि इस ताजे अंक में वीपी का ही बोलबाला है। हमारी समझ में नहीं आता कि 'माया' अपने आकलनों में अतिरेक क्यों करती है? जिस राजा का इलाहाबाद में कोई खास जोर नहीं दिखता, उस राजा को 'माया' बेबात चढ़ाये जा रही है। 'माया' ने कभी राजा से यह भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद के लिए किया क्या है? ईमानदारी का दम भरनेवाले राजा के पीछे कौन लोग हैं, क्या वीसी शुक्ला, अरुण नेहरू, संजय सिंह जैसे लोग, जो कल तक कांग्रेसी संस्कृति मे आकंठ डूबे हुए थे, आज राजा हरिश्चंद्र हो गये हैं। राजा सहित ये सभी लोग जब तक कांग्रेस मे थे, तब तक इनको जनता के दुख-दर्द का खयाल नहीं आया। आज ये लोग जनता का दुख-दर्द बांटने के लिए आतुर दिखायी दे रहे हैं। आपकी आवरण कथा से यह निष्कर्ष निकालना बेजा न होगा कि राजा की जीत हो सकती है, लेकिन राजा बड़े लोकप्रिय हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं क्या इसलिए—नहीं बल्कि इसलिए कि कांग्रेस की नीतियां भ्रष्ट हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजा को जिताने का अगर श्रेय किसी को दिया जायेगा, तो वह होगा अभी हाल में हुई पदयात्रा की नौटंकी, जिसके चलते वीरबहादुर मंत्रिमंडल को अपना-सा मुंह लेकर भागना पड़ा था। राजा यदि जीत भी जाते हैं, तो क्या वह पूरे देश से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खतम कर देंगे, आखिर वह भी तो कांग्रेसी संस्कृति की ही देन हैं, चाहे भले ही वह लोगों की दृष्टि में कीचड़ में कमल हों। **—सुधींद्र राव, वास्को ड गामा, गोवा**

दूध का धुला कौन?

३० अप्रैल '८८ के अंक में 'राजा बनाम शहंशाह' लेख में अमिताभ की आलोचना में कहा गया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास हेतु कोई कार्य नहीं किया है और कि उन्होंने किससे पूछकर व किसके कहने पर संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था तथा अब किसके कहने से पुन: चुनाव लड़ना चाहते हैं?

ये सब बातें शायद न कही जातीं, यदि वह 'अमिताभ' न होकर एक 'सामान्य सांसद' होते। क्या अन्य संसदीय क्षेत्रों में कोई समस्या ही नहीं है? एक बात और—राजीव गांधी तथा उनकी कथित मंडली को भ्रष्ट कहने वाले तथा सुव्यवस्था का प्रतीक कहे जाने वाले, वीपी सिंह क्यों नहीं राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते? किसके वोटों से वह राज्य सभा के सदस्य हैं?

आखिर यह दोगलापन क्यों? उन्होंने जनता को क्या 'मूर्खता की रेखा से भी नीचे' का मूर्ख समझ रखा है? **—राजेशकृष्ण सांचीहर, शाहपुरा, सुनारों का बास, जोधपुर, राजस्थान**

ज्ञानीजी का दोहरा खेल

'माया' के १५ अप्रैल '८८ की आवरण कथा 'ज्ञानीजी का दोहरा खेल, अच्छी लगी। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने यह कहकर कांग्रेसियों को सन्न कर दिया है कि राजीव गांधी की गद्दी पर आर वेंकटरमण, बलराम जाखड़, पीवी नरसिम्हाराव और अर्जुन सिंह आदि आंखें गड़ाये बैठे हैं। सोचने वाली बात है कि आर वेंकटरमण स्वयं राष्ट्रपति हैं, वह राजीव गांधी की गद्दी पर क्यों आंखें गड़ायेंगे? रही बात बलराम जाखड़, पीवी नरसिम्हाराव और अर्जुन सिंह की, तो वे लोग देश के लिए प्राण न्योछावर तक कर सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी से क्या सरोकार! **—ललित कुमार मिश्र, विष्णुगढ़, हजारी बाग**

माथुर-राज में औरत

'माथुर के राज में औरत' (१५ अप्रैल '८८) पढ़कर मन में प्रश्न उठा कि आखिर कब तक सुगना और केसर जैसी मासूम, निर्दोष और निरीह लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता रहेगा और कब तक अपनी क्षणिक शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए निरंकुश घूमने वाले लोग ऐसी अबलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछित घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी न गयी, तो हमें एक बार फिर से आदिम युग से साक्षात्कार करना पड़ेगा।
—राजन चोपड़ा, नयी दिल्ली

बेचारे अधिकारी क्या करें?

१५ अप्रैल की 'माया' में छपा लेख 'कानून का पालन करें या आकाओं के हुक्म की तामील' सामयिक और आज के माहौल में सटीक है। आपने कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति का जो जीवंत चित्रण किया है, वह सराहनीय है। अंगूठा छाप राजनेता मेधावी अधिकारियों को अदूरदर्शितापूर्ण आदेश देकर कुंठित कर रहे हैं। अधिकारी आज अपने विवेक की तिलांजलि देकर मंत्रियों का मुंह ताक रहे हैं। जिलाधिकारियों की बैठक करके वे स्वच्छ प्रशासन नही दे सकते हैं। वेद मरवाह के साथ की गयी करतूत से उनका मंसूबा धरा-का-धरा रह जायेगा।
— सूर्यबली सिंह, प्रधानाचार्य, अंबिकादत्त सिंह विद्यालय, बस्ती

अनुरोध है…

'माया' ने अब (१५ अप्रैल '८८) से पाक्षिकी का एक नया कालम बढ़ा दिया है, यह एक अच्छी बात है। संक्षिप्त घटनाएं इस तरह से हमें क्रमानुसार मिलती रहेंगी। अनुरोध यह जरूर करना है कि 'पाक्षिकी' को सदैव प्रकाशित करने की चेष्टा करें। साथ ही यह भी कहना है कि जिस तरह पिछले अंक (माया: ३१ मार्च '८८) में 'अचानक' जैसा पृष्ठ आपने संलग्न किया था, उसी तरह भविष्य में भी घटनाओं को प्रस्तुत करें। वैसे तो 'माया' में किसी प्रकार की कमी निकालना टेढ़ी खीर-सी है। हमने कुछ लोगों से तो यह भी सुना है कि 'माया' में केवल 'दिल्ली दरबार' ही सब कुछ है। बहरहाल, यह तो अपनी-अपनी समझ की बात है।**—एचबी मणि त्रिपाठी, कुष्ठ नियंत्रण इकाई, गोण्डा**

T-Shirts
Baba Suits
Rocky
IS A AHEAD OF TIME AND
TIME IS AHEAD OF FASHION
available at all leading stores
Marketed by : SUSHIL KNITWEAR
160 , Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 007

रिश्वतखोरो सावधान

'**मा**या' के १५ अप्रैल, १९८८ के अंक में 'रिश्वतखोरो सावधान!' शीर्षक के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (सतर्कता) के उपायुक्त श्री शुजुद्दीन साजिद के बारे में पढ़ा। वैसे तो साजिदजी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहने को कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आज की प्रशासन व्यवस्था जिस कगार पर पहुंच चुकी है, वहां एक कदम भी भ्रष्टाचार के सहारे के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता जो कि एक शर्मनाक तथ्य है। इसलिए यह कहना उचित ही है कि उपायुक्त (सतर्कता) महोदय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनकी कर्तव्यपरायणता के लिए हम धन्यवाद देते हैं व आशा करते हैं कि भविष्य में भी वह इसी तरह देश की सेवा में योगदान देते रहेंगे। देश के अन्य बड़े-बड़े अधिकारियों, नेताओं, व कर्मचारियों को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए व अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए।—**भगत राम फुल, काजीवाड़ापुली, अंबाला शहर, हरियाणा**

कर्ज का फंदा

१५ अप्रैल '८८ की 'माया' पढ़ी। जय दुबाशी के लेख 'कर्ज का कसता फंदा' पढकर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या कभी इस देश की अर्थ व्यवस्था बदलेगी भी या...खैर मैं 'माया' को दिली मुबारकबाद देता हूं ऐसे लेख प्रकाशित करने के लिए।—**ब्रजपाल सिंह, जड़ौदा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**

दीक्षितजी का कहना है...

आपकी पत्रिका के इस मास के अंतिम सप्ताह के अंक (३१ मार्च, १९८८) में ३६वें पन्ने पर 'कांग्रेस के कायाकल्प की योजना' इस शीर्षक का जो लेख छपा है, उसमें मेरे संबंध में जो लिखा गया है, उसके द्वारा मेरे साथ भाषा और भाव दोनों प्रकार से अन्याय किया गया है।

आरंभ मे लिखा गया है कि 'स्वयं पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों के कायाकल्प के लिए एक योजना राजीव गांधी को सौंपी है। कांग्रेस के बुजुर्ग पहरेदार बौखलाये हुए हैं' आप स्वीकार करेंगे कि यह वाक्य अशिष्ट भाषा में है [illegible] कांग्रेस का मैं पुराना सेवक हूं, इसलिए मुझे बुजुर्ग कहा जाये, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, मेरे जैसे वृद्ध कांग्रेसजन अपने को कांग्रेस का पहरेदार मानते हैं और बौखलाये हुए हैं, इस कथन का कोई आधार लेखक के पास क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर मुझको सार्वजनिक रूप में अपमानित करना चाहते हैं। दूसरे पैरे में यह लिखा गया है कि 'इसके क्या प्रमाण हैं कि पित्रोदा ने कांग्रेस-इ पर कोई रिपोर्ट तैयार की है। आखिर कांग्रेस के बारे में वह क्या जानते हैं?' मैं कांग्रेस में ४० साल से हूं और पित्रोदा जैसे नौसिखियों से मुझे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य मैंने किससे और कब कहे, यह उस लेख से प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उसमें संवाददाता का नाम नहीं दिया गया है। वरन् ऐसा लगता है कि संपादकीय विभाग के किसी लेखक ने सुनी सुनायी बात को अधिक रोचक बनाने के उद्देश्य से ऐसी भाषा का उपयोग किया है जैसी भाषा का उपयोग करना मेरे स्वभाव और वर्षों से सर्वपरिचित व्यवहार के सर्वथा प्रतिकूल है। यह मुझे अवश्य स्मरण है कि एक दिन श्री सैम पित्रोदा मुझसे मिलने आये थे और अपनी योजना की प्रति दी थीं और सक्षेप में उसका कुछ वर्णन भी किया था। उसके बाद से मेरा उनसे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। उनकी योजना की कोई प्रति भी अब मुझे उपलब्ध नहीं है।

यह सच है कि उनको कांग्रेस के पुराने इतिहास का परिचय व अनुभव नहीं है, परंतु यह कहना अनुचित होगा कि वह कांग्रेस के उत्थान के हित में कोई अच्छी या नयी योजना तैयार नहीं कर सकते हैं। मेरा स्वयं का मत है कि कांग्रेस का विधान और उसके नियम जो महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय उपयोगी मानकर निर्मित किये गये थे, वे आजादी के ४० वर्षों के बाद अब बहुत अंशों में असुविधाजनक और कहीं-कहीं निरर्थक एवं हानिकारक हो गये हैं। परंतु उनके स्थान पर कांग्रेस विधान की ऐसी नवीन योजना का निर्माण करना, जो सर्वथा निर्दोष हो और कांग्रेसजनों को संतोषकारक और स्वीकार्य हो, आसान नहीं है। परंतु उस दिशा में कोई कदम ही न उठाया जाये, यह कहना आपत्तिजनक होगा।—**उमाशंकर दीक्षित, १, सरकुलर रोड, नयी दिल्ली**

मुझे हिंदुओं की चिंता है, वरना मैं कभी का फिर से कार्टूनिस्ट बन जाता, मेरे दिल को चीर कर देखिए, मेरे मन में हिंदुओं के लिए कितना स्नेह है।—**शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे 'रविवार' में।**

अमिताभ बच्चन इलाहाबाद दो बार आये, स्विट्जरलैंड आठ बार गये।—**वीपी सिंह**

स्वर्ण मंदिर और दूसरे सिखों के गुरद्वारे ऐसे लगते हैं, जैसे भारत में पाकिस्तानी द्वीप। —**जेएस उमरनांगल, अकाली दल (लों) के उपाध्यक्ष**

पंजाब भारत का सिर है, अगर सिर कट गया, तो क्या शरीर (भारत) जिंदा रह सकेगा? —**वसंत साठे**

कांग्रेस में भी कमजोरियां हैं, हम कब कहते हैं कि हम सर्वगुणसंपन्न हैं।—**प्रधानमंत्री राजीव गांधी**

आखिर केंद्रीय गृह मंत्रालय किस मर्ज की दवा है जो तमाम चौकसियों की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान पंजाब को दनादन हथियार दिये जा रहा है।—**शिरोमणि अकाली दल (मा० तारा सिंह) के जत्थेदार रछपाल सिंह**

पंजाब में जो हिंसा का तांडव चल रहा है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमने नयी नस्ल को 'अहिंसा' का पाठ नहीं पढ़ाया।—**आचार्य सुशील मुनि**

भारत सरकार को यह पता ही नहीं है कि उसे पंजाब में क्या करना चाहिए।—**खुशवंत सिंह**

कांग्रेस छोड़ने वाले हरियाणा के विधायक तैयब हुसैन 'आदतन दलबदलू और राजनीतिक ब्लैक मेलर' हैं।—**कृषि मंत्री भजनलाल 'जनसत्ता' में**

अब आप ७७ का नाम ही न लीजिए। आज ये सड़ा हुआ समाज है। सड़ा हुआ सार्वजनिक जीवन है। सड़े हुए राजनीतिक दल हैं। सड़े हुए नेता हैं। १९७७ में, फिर भी, राजनीतिक दलों की अच्छी स्थिति थी।—**मधु लिमये, 'चौथी दुनिया' में**

श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वर्णमंदिर पर हमला करने की कीमत जान देकर चुकानी पडी, अब सिद्धार्थ शंकर रे और जेएफ रिबेरो को भी नहीं बख्शा जायेगा। दोनों को सजा देकर ही हम दम लेंगे।—**गुरजीत सिंह**

जार्ज बुश (अमरीका के उपराष्ट्रपति) में इतनी काबिलीयत नहीं कि वह अमरीका के राष्ट्रपति बन सकें।—**पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन**

दिलीप वेंगसरकर रवि शास्त्री से बेहतर कप्तान हैं।—**करसन घावरी**

मैं सीता की तरह जीना बिलकुल पसंद नहीं करूंगी, मैं ढोंग करना नहीं चाहती, जैसी हूं वैसे ही जीना चाहती हूं।—**अरुण गोविल की पत्नी लेखा गोविल**

मेरे जीवन में खूबसूरत जवां मर्द आ चुका है। वह शादीशुदा है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़नेवाला।—**डिंपल कपाड़िया**

राजीव गांधी

मधु लिमये

लेखा गोविल

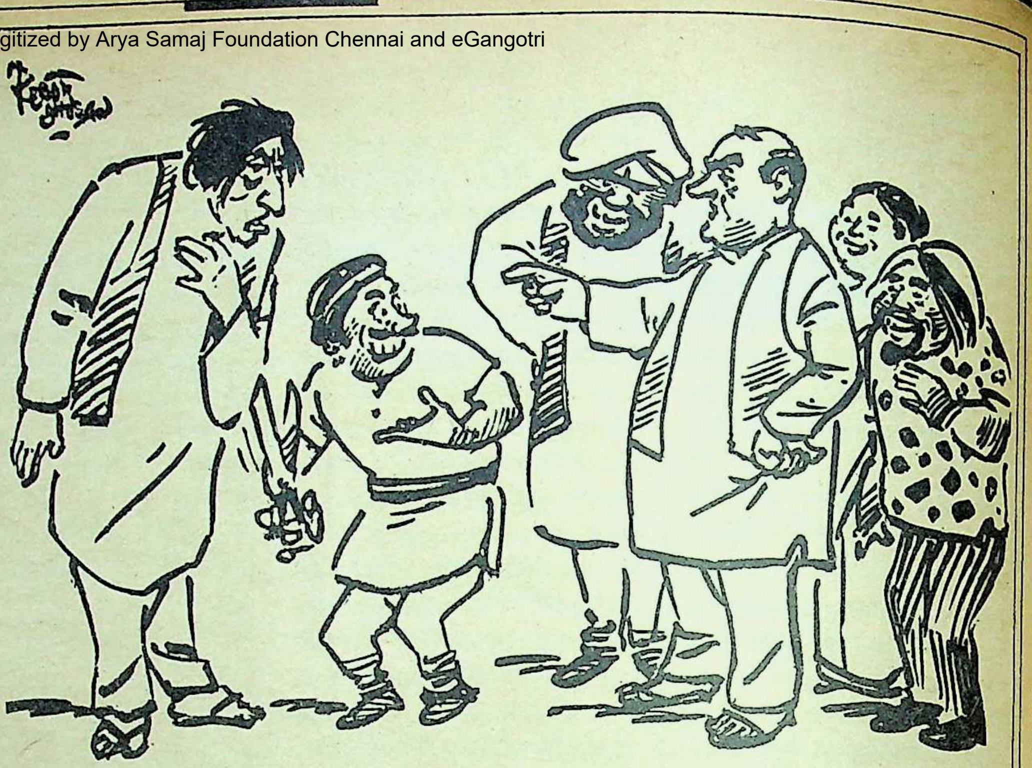

अमिताभ के नाई का नुस्खा

जार्ज ने दिल्ली दरबार के कान में फुसफुसाया, "सर, वह चैनल न० ००७ पर अमिताभ बच्चन इंतजार...।" दिल्ली दरबार ने जार्ज से इशारे में कहा कि कंट्रोल रूम को कहो कि अमि को चैनल न० नौ-दो-ग्यारह पर लेकर इसी वीडियो स्क्रीन पर दे दो। पास खड़े सैम पित्रोदा ने जैसे ही दिल्ली दरबार के इशारे को भांपा, तो वह जार्ज के करीब लपक लिये, "जार्ज अमि को चैनल नौं-दो-ग्यारह पर मत लेना। यह अपोजीशन का चैनल है। इस चैनल पर वीपी सिंह बहुत हाई वोल्टेज पर चढ़ा हुआ है। अमिताभ जैसे ही इस चैनल पर आयेगा, उसका 'फ्यूज' उड़ जायेगा।" जार्ज ने फिर कान में फुसफुसाया, तो दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये, "शहंशाह के रिलीज हो जाने के बाद भी अमिताभ का वोल्टेज वीपी सिंह के वोल्टेज से कम नहीं है। इसे कतई बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारा बिजली संत्री वसंत साठे तो कह रहा था कि शहंशाह मुल्क में इतनी बिजली पैदा कर देगा कि हमको अपने सारे पावर हाउस बंद कर देने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली सरप्लस हो जायेगी। मुझे फौरन एक रिपोर्ट (टीवी फिल्म) दी जाये कि शहंशाह ने मुल्क में कितना पावर पैदा किया है।" जार्ज से जब बात न संभली, तो कैप्टन सतीश शर्मा आगे हो लिये, "सर, शहंशाह ने बिजली तो बहुत पैदा की, लेकिन हमारे घटिया किस्म के संयंत्र उसे स्टोर कर पाने में सफल नहीं हो पाये। इसी लिए कुछ प्रोबलम हो गयी।" दिल्ली दरबार गरजे, "यह संयंत्र पब्लिक सेक्टर के होंगे।" सतीश शर्मा कुछ बोलें कि इसके पहले मनटेक सिंह अहलूवालिया आगे आ गये, "यस सर, हमारी मुख्य समस्या यही है। जब तक हम लोग देशी संयंत्र के सहारे चलेंगे, तब तक शहंशाह टाइप के पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। अब सर, आप ही देखिए, अपने अमिताभ ने कितनी मेहनत से शहंशाह के जरिये करोड़ों मेगावाट बिजली पैदा कर दी, लेकिन वह हमारे किसी काम की नहीं रही। हम लोगों का तो एस्टीमेट था कि कम-से-कम इस शहंशाह के पावर से साढ़े चार सौ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रोशन हो जायेंगे। लेकिन देशी संयंत्र होने के कारण हम लोग इलाहाबाद तक में एक बल्ब नहीं टिमटिमा पाये। सर, अगर आप कहें, तो हम लोग संयंत्रों का इम्पोर्ट शुरू कर दें।" अहलूवालिया नें 'संयत्रों के इम्पोर्ट' के लालच में अपनी जीभ को लपलपाने की जगह अपनी दाढ़ी खोलकर लपलपा दी। इसी बीच सैम पित्रोदा गुस्से में अपनी बुलगानियन कट दाढ़ी को नोचते मनटेक सिंह पर चढ़ लिये, "मैं दरबार का तकनीकी सलाहकार हूं। कौन सा संयंत्र इम्पोर्ट होगा, कौन सा नहीं, यह मैं तय करूंगा। तुम अपने को इस बात तक ही सीमित रखो कि दरबार को कहां-कहां से उधार मिलेगा। तुंम अपने को आर्थिक मामलों तक ही रखो, नहीं तो मैं एक टेलीफोन एक्सचेंज तुम्हारी दाढ़ी में फिट कर दूंगा और तुम घनघनाते (हिनहिनाते) रहोगे।" कैप्टन सतीश शर्मा ने सैम पित्रीदा को पुचकारते हुए पीछे से कहा, "अरे सैम, इसमें इतना लड़ाई-झगड़ा काहे को कर रहे हो। संयंत्र इम्पोर्ट करने में कोई परेशानी दिल्ली दरबार को नहीं है। हां, बस उसकी दलाली (कमीशन) में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो बड़ी मुश्किल से उस बोफोर्स से हम लोग निकल पा रहे हैं।" सैम पित्रोदा कुछ ढीले पड़े, तो जार्ज ने आगे बढ़कर दिल्ली दरबार के कान में फिर से फुसफुस की, "सर, वह अमिताभजी चैनल न० ००७ की टीवी स्क्रीन पर बहुत लाल-पीले हो रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका बारबर (नाई) उनके पीछे पड़ा हुआ है।"

दिल्ली दरबार बारबर (नाई) की बात को सुनकर खिलखिला दिये, तो सारे दरबारी भी उस खिलखिलाहट में समवेत स्वर से शामिल हो गये। सीताराम केसरी इतना खिलखिलाये कि सोफे से नीचे फर्श पर लोट-पोट हो गये। गुलाम नबी आजाद ने खिलखिलाहट का तुरन्त फायदा उठाकर 'पार्टी पुनर्गठन' की फाइल को दिल्ली दरबार के सामने से उठाकर अपनी शेरवानी में छुपा लिया। लेकिन पीछे लाइन में खड़े सोलंकी-पहाड़िया-मिश्र की तिगड्डी ने उसे देखकर काना-फूसी शुरू कर दी। किसी ने खिलखिलाहट की आड़ में कमरे की बत्ती गुल कर दी। बूटा सिंह के खिलखिलाहट से बाहर निकलने के पहले ही चिदम्बरम ने तुरन्त निकल कर गुल बत्ती को रोशन कर दिया। दरबार की बत्ती गुल कर देने के षड्यंत्र पर बूटा सिंह कोई न्यायिक जांच बिठाने की सोच रहे थे कि जिमनास्टिक करती हुई शीला दीक्षित एचकेएल भगत पर आ गिरीं। भगतजी उठे और भुनभुनाने लगे। भगतजी की कुढ़न की परवाह किये बिना शीला दीक्षित ने ब्लाउज में मोड़कर रखी 'चिट्ठी' दिल्ली दरबार की नजर कर दी। 'चिट्ठी' देखते ही न्यू दिल्ली तिवारी (नारायण दत्त तिवारी) फड़क उठे और उन्होंने गाना शुरू कर दिया, "चिट्ठी आयी है...आयी है...बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की आयी है, चिट्ठी आयी है।" दिल्ली दरबार चिट्ठी के बारे में शीला दीक्षित से कुछ पूंछे कि तिवारी के

स्वर में कई दरबारी शामिल हो गये। केसरीजी से न रहा गया और उन्होंने धूल खा रही पेटी (हारमोनियम) को खींच लिया और लहरा देने लगे। गुलाम नबी आजाद ने शेरवानी में छिपी पार्टी पुनर्गठन की फाइल की परवाह किये बगैर मेज को तबला बनाकर ठेका लगाना शुरू कर दिया। पूरे दरबार में 'चिट्ठी आयी है, चिट्ठी आयी है...' गूंजने लगा। इसी बीच जब गुलाम नबी आजाद ठेका लगाने में ज्यादा मशगूल हो गये, तो डा० जगन्नाथ मिश्र ने माधव सिंह सोलंकी को इशारा किया कि गुलाम नबी की शेरवानी में छिपी फाइल निकाल कर दिल्ली दरबार के सामने पेश कर दो। सोलंकी थोड़ा हिचकिचाये, तो मिश्र ने पहाड़िया को इशारा किया। पहाड़िया ने 'चिट्ठी आयी है, आयी है...' के साथ धोबीपाट मार कर गुलाम नबी आजाद की शेरवानी से फाइल को निकाल लिया।

फाइल बाहर आते ही गुलाम नबी की तबले के साथ, बोलती भी बंद हो गयी। केसरीजी की उंगलियां पेटी पर रुक गयीं। लेकिन तिवारीजी 'चिट्ठी आयी है, आयी है...' का सस्वर पाठ करते रहे और अधिकांश दरबारी उसमें अपना स्वर मिलाते रहे। जगन्नाथ मिश्र ने पहाड़िया के हाथ से फाइल छीनकर दिल्ली दरबार की तरफ उछाल कर फेंक दी, ''सरकार, मुझे देश (बिहार) छुड़वाकर पार्टी संगठन में एडजस्ट करने के लिए बुलवाया। लेकिन यह गुलाम का बच्चा...।'' जगन्नाथ मिश्र का वाक्य जगन्नाथ पहाड़िया ने छीन लिया, ''हुजूर यह गुलाम नबी का बच्चा पहाड़ के नीचे अपना कद पहचानने के लिए नहीं आना चाहता। इसीलिए जब आप 'खिलखिलाये', तो मौका पाकर इसने पार्टी पुनर्गठन की फाइल आपके सामने से उठाकर अपनी शेरवानी में छिपा ली।'' पहाड़िया के चिल्लाने पर तिवारीजी की 'चिट्ठी आयी है... का स्वर मंद पड़ गया। बाकी सभी दरबारियों के स्वर भी थम-से गये। सोलंकी ने अपने गोल्डन फ्रेम के चश्मे से लाल-लाल आंखें बाहर निकालीं, ''इस गांधी नगर से हमारा वह गांधी नगर (अहमदाबाद) ज्यादा अच्छा था। इस गांधी नगर में तो दिन दहाड़े चोरी-छिनारी चल रही है। वहां तो अभी भी यह सब कुछ लुक-छुप कर होता है।'' सोलंकी की बात पर बूटा सिंह को ताव आ गया, ''अभी आये जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए, इस गांधी नगर में तुमको हर तरफ बुराई-बुराई नजर आने लगी। अरे गुलाम नबी ने दिल्ली दरबार से दिल्लगी में फाइल चुरा ली, तो कौन सा पहाड़ आ गिरा। हम लोग इस तरह की चुहलबाजी करते ही रहते हैं।''

नाई ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया—''सर, मैं इलाहाबाद चुनाव लड़ने की बात कहता हूं, तो अमिताभजी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। मुझे बाल काटने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए उनके मना करने पर भी इलाहाबाद से चुनाव लड़ने की बात कह देता हूं। हुजूर यह मेरी रोजी-रोटी का सवाल है।'' सारे दिल्ली दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। वह नाई टुकुर-टुकुर इधर-उधर देखता रहा।

सोलंकी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जगन्नाथ मिश्र भिड़ गये, ''देखिए बूटा सिंहजी, हम लोग यहां चुहलबाजी करने के लिए नहीं आये न! यह बहुत ही सीरियस मैटर है। हम लोगों का जल्द ही पूरा-का-पूरा एडजस्टमेंट होना चाहिए। घर-बार छोड़कर कुछ कमाने के लिए ही निकले हैं न। नौकरी तुरन्त मिलनी ही चाहिए। इस तरह गुलाम नबी फाइल चुरायेगा, तो दंगा-फ़साद हो जायेगा।'' अब दिल्ली दरबार से न रहा गया, तो वह चीख पड़े, ''यह दरबार है या नौटंकी घर।'' दरबार की चीख सुनकर सुरक्षा की काली बिल्लियां स्टेनगन लेकर मिउं...मिउं...करके चौक्कनी होने लगीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार ने शीला दीक्षित की ओर मुखातिब होकर ऊंचे स्वर में पूछा, ''यह किसकी चिट्ठी है! मैं २१वीं शताब्दी में जाने के लिए बैठा हूं और मुझे इस १६वीं सदी के घटिया ढंग से मैसेज दिया जा रहा है। कंप्यूटर के जरिये यह चिट्ठी क्यों नहीं दी गयी?'' शीला दीक्षित कमर से दिल्ली दरबार के हुजूर में दोहरी हुईं, लेकिन मुड़ न पाने के कारण, धड़ाम से जमीन पर आ गिरीं। भगतजी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वह शीला दीक्षित से काफी दूरी पर थे। शीलाजी ने तुरन्त फिर से खड़े होकर जितना झुक पायीं, झुककर अर्ज किया, ''सरकार, यह चिट्ठी मेरे ससुर ने आपके पास भिजवायी है।'' दरबार ने बात बीच में ही काट दी, ''ससुर या फादर-इन-ला।'' शीलाजी ने अपने को तुरन्त ठीक किया, ''जी सर, ससुर नहीं फादर-इन-ला।'' दरबार ने पास खड़े जार्ज को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, ''उमाशंकर दीक्षित की इस चिट्ठी को सूंघ कर इसका मजमून बयान करो।'' जार्ज ने गहरी सांस लेकर चिट्ठी को सूंघा और बयान करना शुरू कर दिया, ''सर, इस बुड्ढे का कहना है कि अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कतई मत लड़ाओ। वह राजा मांडा से हार गया, तो लेने-के-देने पड़ जायेंगे। अगर वीर बहादुर उसे किसी तरह हेराफेरी करके जिता भी लाया, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।'' दिल्ली दरबार आपे से बाहर होकर गरजे, ''हमने इस बूढ़े की कब राय मांगी थी। शीला दीक्षित को जूड़ी का बुखार चढ़ने लगा। तभी धड़ाम की आवाज हुई, तो सारा दरबार सकते में आ गया। अमिताभ बच्चन चैनल न० ००७ की टीवी स्क्रीन को तोड़कर बाहर निकल आये। उनके पीछे उनका बारबर (नाई) हाथ में कैंची लिये हुए पीछा कर रहा था। सुरक्षा की काली बिल्लियों ने बारबर को स्टेनगन के बीच रोक लिया, तो अमिताभ बच्चन की सांस-में-सांस आयी।

दिल्ली दरबार की समझ में नहीं आ पा रहा था कि माजरा क्या है? उसने अमिताभ से पूछा, ''यह क्या चक्कर है? यह नाई कैंची लिये तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा है?'' अमिताभ बच्चन ने कहा, ''यार, सांस ले लें, तो बतायें।'' पानी का पूरा जग अंदर करने के बाद अमिताभ ने सन्नाटा खाये दिल्ली दरबार से आप बीती सुनानी शुरू की—''यह बारबर हर १५ दिन में मेरे बाल काटने के लिए जब भी आता, तो आते ही कहता कि बच्चन साहब आप इलाहाबाद से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जैसे ही यह इलाहाबाद का नाम लेता, मेरे बदन में कंपकंपी शुरू हो जाती। मैंने इसको कई बार मना किया, लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आता है। इस बार इसको देखते ही मैं भाग लिया, तो यह अपनी कैंची लेकर मेरे पीछे हो लिया और इसने मेरा यहां तक पीछा किया।''

दिल्ली दरबार अमिताभ की करुण गाथा सुनकर गुस्से से पागल-सा हो उठे, ''इस नाई को मेरे सामने हाजिर करो।'' सुरक्षा की काली बिल्लियां स्टेनगनों के बीच उस नाई को दरबार के सामने ले आयीं। दिल्ली दरबार गरजे, ''कहां का रहने वाला है?'' नाई ने अपनी कैंची चलाते हुए जवाब दिया, ''हुजूर गोरखपुर का।'' दरबार ने तुरन्त कुछ पहचानने की मुद्रा बनाते हुए पूछा, ''कहीं तुम्हारा नाम वीर बहादुर सिंह तो नहीं है।'' नाई बोला, ''नहीं सरकार, वह तो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे चीफ मिनिस्टरी वाला काम बिलकुल पसंद नहीं है। मैं तो अमिताभजी का बारबर हूं।''

दिल्ली दरबार फिर गरजे, ''तुम अमिताभ के बाल काटते समय इलाहाबाद चुनाव की बात क्यों करते हो?''

नाई ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया—''सर, मैं इलाहाबाद चुनाव लड़ने की बात कहता हूं, तो अमिताभजी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। मुझे बाल काटने में आसानी हो जाती है। इसीलिए उनके मना करने पर भी इलाहाबाद से चुनाव लड़ने की बात कह देता हूं। हुजूर यह मेरी रोजी-रोटी का सवाल है।'' सारे दिल्ली दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। वह नाई टुकुर-टुकुर इधर-उधर देखता रहा।

—**दरबारी लाल**

युवक कांग्रेस में तख्ता पलट

आस्कर फर्नांडिस

युवक कांग्रेस के अध्यक्ष गुरुदास कामत के इस्तीफा देने के पीछे मुख्य रूप से इंका के प्रभावशाली महामंत्री आस्कर फर्नांडिस का हाथ है। लेकिन कामत की जगह सुधा जैकब को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में आस्कर सफल नहीं हो पाये। इसमें बाजी मार ले गये इंका के दूसरे प्रभावशाली महामंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद ने कुछ ऐसी जोड़-तोड़ की कि अपने खास आदमी मुकुल वासनिक को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। अब आजाद को और मुकुल वासनिक दोनों इस जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं कि आस्कर फर्नांडिस से युवक कांग्रेस का प्रभार छीन लिया जाये। गुलाम नबी आजाद चाहते हैं कि युवक कांग्रेस के इंचार्ज वह स्वयं बना दिये जायें। इंका क्षेत्रों में यह उम्मीद भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जल्द ही युवक कांग्रेस का चार्ज गुलाम नबी को दे देंगे। लेकिन कांग्रेस के एक और महामंत्री वी पणिक्कर इस फिराक में लगे हैं कि युवक कांग्रेस का चार्ज उनको मिल जाये।

युवक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गुरुदास कामत का खुला आरोप था कि आस्कर फर्नांडिस ने प्रारंभ से ही उनके सामने परेशानियां पैदा करना शुरू कर दिया था। जब वह शिकायत लेकर इंका अध्यक्ष राजीव गांधी के पास गये, तो वहां भी उनकी बातों को नहीं सुना गया। राजीव गांधी के निजी सचिव वी जार्ज, जो आस्कर के 'गाडफादर' हैं, ने उनके खिलाफ अंदर-ही-अंदर मुहिम चला रखी थी। इसीलिए उन्होंने दुखी होकर पद त्याग दिया।

गुरुदास कामत का यह भी आरोप है, "अकसर आस्कर रात को मुझे युवक कांग्रेस की समस्याओं पर बात करने के लिए जब बुलाते थे, तो वहां युवक कांग्रेस की एक महामंत्री सुधा जैकब (पुत्री स्व० सीएम स्टीफन) पहले से ही मौजूद रहती थी। कई बार मैंने आस्कर से कहा भी कि सुधा जैकब के सामने मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन आस्कर का कहना था कि जब भी मैं बात करूंगा सुधा वहां जरूर रहेगी।" कामत का यह भी आरोप है कि आस्कर की शह पर सुधा जैकब ने युवक कांग्रेस के कार्यालय पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। "मेरे आदेश की जगह मेरे कार्यालय में सुधा के ही आदेश चलते थे।"

कामत ने समय-समय पर आस्कर के बारे में जो शिकायतें राजीव गांधी को भेजी थीं, उनका कोई अता-पता नहीं चल रहा है। गुलाम नबी आजाद अब कामत से उन आरोप पत्रों की प्रतियां लेकर किसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भिजवाने की फिराक में हैं। आजाद इस काम के लिए इंका के कोषाध्यक्ष सीता राम केसरी को फांस रहे हैं कि वह राजीव गांधी को ये सारी चीजें बतायें। केसरीजी अभी काफी टाल-मटोल कर रहे हैं, क्योंकि केसरीजी वी जार्ज को नाराज करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। आजाद जार्ज के नाराज हो जाने के डर से फर्नांडिस के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे।

भोपाल की लड़ाई दिल्ली में

अर्जुन सिंह

मोतीलाल वोरा के केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय में आ जाने के बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गयी हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद अर्जुन सिंह ने सबसे पहले दो-तीन को छोड़कर बाकी सभी, मोतीलाल वोरा तथा माधव राव सिंधिया के लोगों को सरकार में शामिल न करके, दोनों कसकर धक्का मारा। उसके बाद अर्जुन सिंह ने वोरा के चहेते अधिकारियों के तबादले करना शुरू कर दिया। वोरा ने जब प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया, तो फिर दिल्ली से अर्जुन सिंह को संयम बरतने के लिए निर्देश जारी हुए। लेकिन उस समय तक अर्जुन सिंह वोराजी को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे।

अर्जुन सिंह ने दिल्ली में अपनी राजनीति को चलाने के लिए सांसद सुभाष यादव तथा अजित जोगी को चुना है। सुभाष यादव को किसानों से संबंधित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। वह भरपूर सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके अर्जुन सिंह की राजनीति कर रहे है।

दूसरी ओर अर्जुन सिंह के कट्टर विरोधी सांसद दिलीप सिंह भूरिया मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमाये हुए हैं। वोरा और सिंधिया का भूरिया को पूरा समर्थन मिला हुआ है। भूरिया ने वोरा और सिंधिया के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। ये सभी लोग मध्य प्रदेश का व्यापक दौरा कर रहे हैं और इंका का आधार मजबूत करने की आड़ में गुपचुप रूप से अर्जुन सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं।

इसी बीच अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम को लेकर व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इसमें सुभाष यादव भी पूरी तरह शामिल हैं। मोतीलाल वोरा और माधव राव सिंधिया तो अपने कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट स्वयं सीधे राजीव गांधी को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अर्जुन सिंह अपनी रिपोर्ट अजित जोगी के जरिये सोनिया गांधी को भिजवा रहे हैं।

अर्जुन सिंह जब केन्द्र में संचार मंत्री थे, तो उनको तुगलक रोड पर सरकारी बंगला मिला हुआ था। उस बंगले को अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश के सरकारी गैस्ट हाउस में बदल दिया है। अर्जुन सिंह दिल्ली करीब-करीब हर सप्ताह धमकते हैं। उनके तुगलक रोड स्थित बंगले पर देर रात तक मप्र के इंकाई सांसद गुफ्तगू करते रहते हैं। वोरा और सिंधिया को इससे काफी परेशानी होने लगी है। लेकिन अब ये दोनों मिलकर अर्जुन सिंह के लिए काफी परेशानी पैदा करने पर पूरी तरह उतारू हैं। अब यही देखना है कि इन लोगों की आपसी लड़ाई कुछ रंग लायेगी या दोनों ही पक्ष ढीले पड़ जायेंगे।

मज़ेदार! असरदार!!

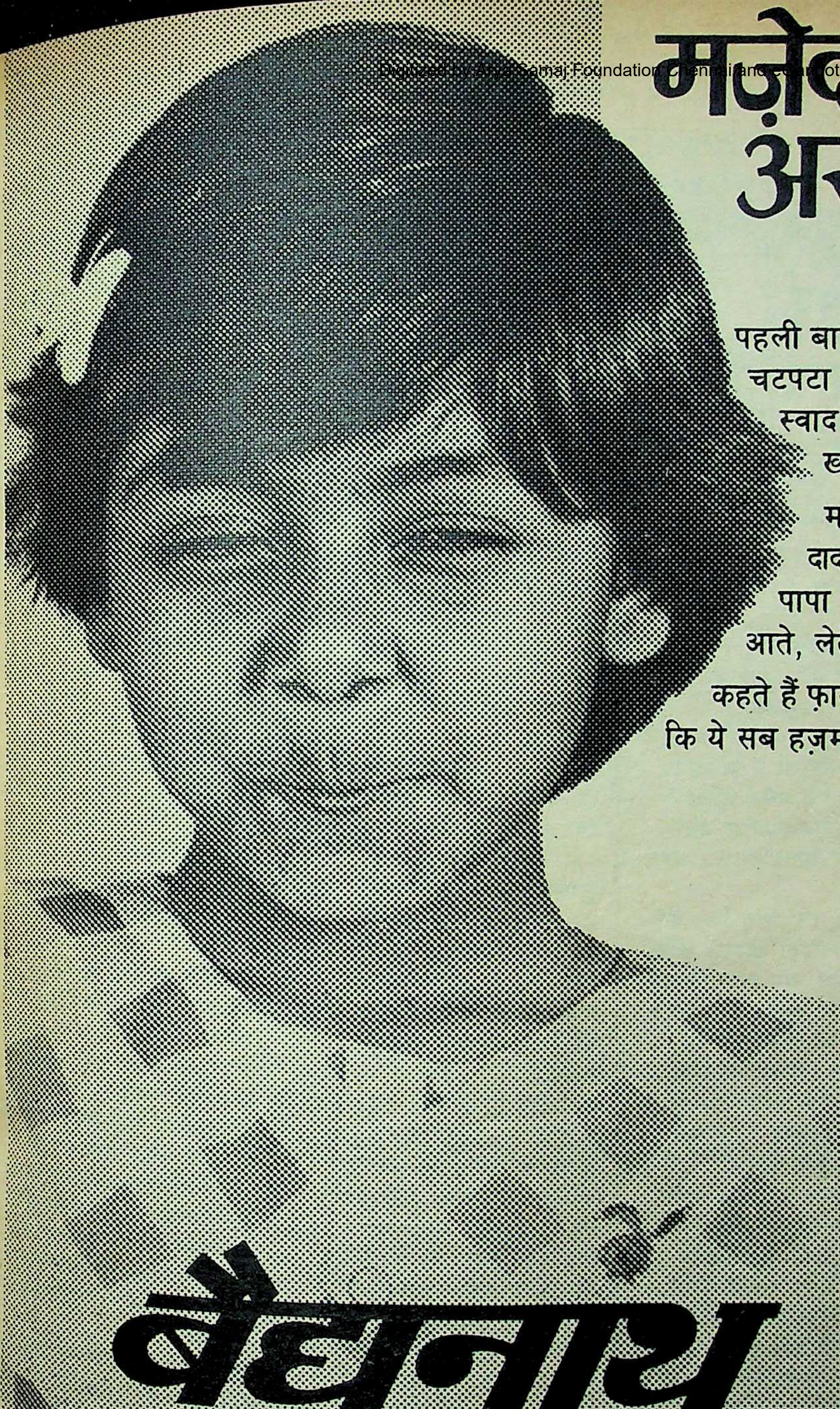

पहली बार जब मैंने हज़मयम खाया, लगा
चटपटा और मज़ेदार! खट्टा-मीठा
स्वाद जो आया, मन करता है
खाँऊ बार-बार।

मम्मी कहतीं खाती हैं जब लगती नहीं भूख,
दादाजी कहते बदहज़मी होती इससे दूर।
पापा भी जब दावत खा कर
आते, लेते हैं जरूर।

कहते हैं फ़ायदा होता है, पर मुझे लगता है
कि ये सब हज़मयम खाने के बहाने हैं।

Baidyanath
HazamYum
बैद्यनाथ

बैद्यनाथ हज़मयम

चटपटी चूरन गोलियाँ

Sista's-BAB/048 B/HIN

पाकिस्तान में सिर्फ २४ लाख हिंदू

विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या दो करोड़ थी जो इन ४० सालों में बढ़ने के बजाय सिर्फ २४ लाख रह गयी है। पाकिस्तान से भारत आये हिंदू तीर्थयात्रियों ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वे शेष बचे २४ लाख हिंदू भी भारत आना चाहते हैं।

देशभर में १९८५ और १९८६ में ४१ हजार महिलाओं ने आत्महत्या की।

सर्वोच्च न्यायालय में एक लाख, ८१ हजार ४६६ मामले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

पूरे देश में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ २९४६ है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा संस्कृत लिखायी है। बिहार में सर्वाधिक ११७४ संस्कृत भाषी हैं, जबकि मेघालय में सिर्फ एक। देश में दस राज्य ऐसे हैं, जहां एक भी संस्कृतभाषी नहीं है। पहली जनगणना (१९५१) के समय केवल एक व्यक्ति ने अपनी मातृभाषा संस्कृत लिखायी थी।

एक आकलन के अनुसार पंजाब में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या करीब दो हजार है तथा छह हजार से अधिक महिलाएं इन्हें हर प्रकार का सहयोग दे रही हैं।

मलेरिया उन्मूलन के दावे के बावजूद भारत में गत वर्ष १८ लाख लोग मलेरिया रोग से पीड़ित हुए। १९७६ में जब देश में मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया गया था, तब मलेरिया रोगियों की संख्या ६४ लाख तक पहुंच गयी थी।

यूरोप में एड्स रोगियों की संख्या १२४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।

फुटपाथ पर सोते हुए ४० लोगों को लोहे के राड से मार डालनेवाले कुख्यात कनपटीमार रमन राघव की एक स्थानीय अस्पताल में ८ अप्रैल को मौत हो गयी। वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। एक समय बंबई में उसका ऐसा आतंक था कि लोगों ने फुटपाथ पर सोना बंद कर दिया था।

दिल्ली की कुल ६०० झुग्गी-झोंपड़ बस्तियों में १५ लाख १७ हजार ७०७ लोग रहते हैं। झोंपड़ियों की संख्या २ लाख, ६७ हजार ५३३ है।

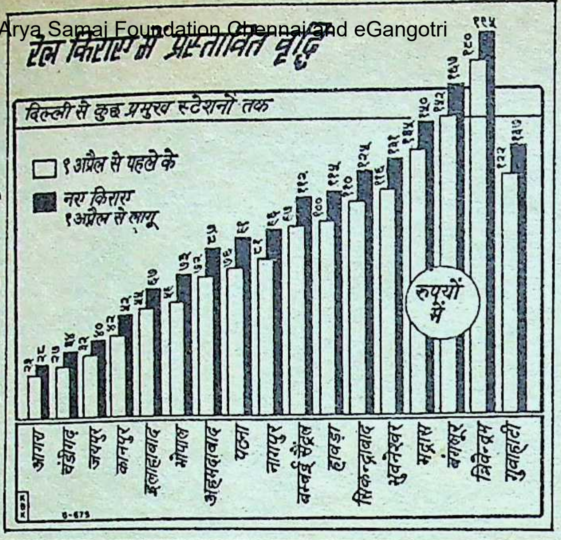

दिल्ली में पिछले साल (१९८७) ३११ लोगों की हत्याएं हुईं, जिनमें १०६ महिलाएं थीं।

१९८६ और १९८७ के दौरान देश के कई हिस्सों में हथियार बनाने के ४२३ अवैध कारखाने पकड़े गये। सबसे ज्यादा अर्थात ३५७ अवैध कारखाने उत्तर प्रदेश में थे।

१९८६-८७ तथा चालू वित्त वर्ष में 'बोकाजान' को छोड़कर सीमेंट निगम के शेष आठ कारखाने घाटे पर चले और उन्होंने २२५३.२१ लाख रुपए का घाटा दिया।

३१ जनवरी, १९८८ तक देश के कुल करीब सात लाख गांवों में से ४ लाख २६ हजार ३२३ गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

जापान सरकार दिल्ली से आगरा होते हुए कानपुर तक के ४२० किलोमीटर रेलमार्ग पर बुलेट रेलगाड़ी चलाने के लिए भारत सरकार को तकनीकी ज्ञान देने के लिए राजी हो गयी है। जापानी विशेषज्ञों की मान्यता है कि भारत में जमीन और श्रम सस्ती दरों पर उपलब्ध होने के कारण बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे लाइन बिछाने पर जापान के मुकाबले एक तिहाई कम खर्च आयेगा। इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार २५० किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

पंजाब में बैंकों की सुरक्षा के लिए भारत-तिब्बत सीमा की छह नयी बटालियनें तैनात की जा रही हैं।

१९७३-७४ की कीमतों के आधार पर गरीबी की परिभाषा तय की गयी थी कि गांवों में रहनेवाले जिस व्यक्ति की क्रय क्षमता ४५ रुपए ९ पैसे और शहर में रहनेवाले की ५६ रुपए ६४ पैसे प्रतिमास या इससे कम है, वह गरीब है। दस साल बाद १९८३-८४ की कीमतों के आधार पर गरीबी की नयी परिभाषा बनी, जिसके अनुसार १०१ रुपए, ८० पैसे प्रतिमास तक की क्रयक्षमता रखनेवाला ग्रामीण और ११७ रुपए ५० पैसे तक की क्रयक्षमता रखनेवाला शहरी गरीब माना गया है। इसके अनुसार गांवों की ४० प्रतिशत और शहरों की २८.१ प्रतिशत आबादी गरीब है।

एक दर्जन सुरंगों और १६१ पुलों से होकर गुजरनेवाली ५३.२ किमी लंबी जम्मूतवी-ऊधमपुर बड़ी रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। इस रेल लाइन पर निर्माणरत दूधर पुल की ऊंचाई ६८ मीटर अर्थात कुतुबमीनार से ऊंची होगी तथा सरदान नदी पर बननेवाला ६६०१ मीटर लंबा पुल देश का सबसे लंबा पुल होगा। २३८० मीटर लंबी सुरंग भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी। श्रीमती गांधी द्वारा १४ अप्रैल, १९८३ से प्रारंभ १०५ करोड़ की इस परियोजना के १९९२ तक पूरा हो जाने की आशा है।

रूस ने चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मस्तिष्क का मामूली आपरेशन करके मनुष्य को इस काबिल बनाया जा सकता है कि वह तीन सौ वर्षों तक जीवित रह सके। चूहे औसतन दो वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन जिन चूहों के मस्तिष्क का आपरेशन किया गया, वे तीन वर्ष तक जीवित रहे।

मलेशिया ने पिछले तीन वर्षों में नशीले पदार्थों की बिक्री के आरोप में ८५ लोगों को फांसी की सजा सुनायी, जिनमें ६२ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है, शेष फांसी का इंतजार कर रहे हैं।

दक्षिण एशियायी देश सैनिक साज सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अमरीकी सरकार द्वारा 'विश्व सैनिक खर्च' के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार १९८५ में भारत का सैनिक खर्च ७.४९३ अरब डालर, पाकिस्तान का २.३७८ अरब डालर, बांग्लादेश का २५ करोड़ ३० लाख डालर और श्रीलंका का १६ करोड़ ७० लाख डालर था।

अमरीकी सूत्रों के अनुसार कुछ दक्षिण एशियाई देशों की सेना की संख्या इस प्रकार है—भारत-१५ लाख १५ हजार, वियतनाम-१० लाख, पाकिस्तान-छह लाख ४४ हजार, बांग्लादेश-९१ हजार, नेपाल-२५ हजार और श्रीलंका-२१ हजार।

भारतीय नौ सेना के ३० अधिकारी और कैडेट १०३ टन की पाल नौका 'वरुण' में २८ हजार किलोमीटर की आस्ट्रेलिया यात्रा पूरी करके १५ अप्रैल को वापस बंबई पहुच गये। पाल नौका से समुद्र यात्रा का यह पहला अभियान था। यह भारतीय दल आस्ट्रेलिया में ब्रिटेनवासियों के पहुंचने की दो सौवीं वर्षगांठ के मौके पर राजधानी सिडनी में हुई पाल नौका परेड में भाग लेने गया था।

ऐसी युवा महिलाओं की संख्या बीस लाख है, जो कालेज में पढ़ती हैं या जिन्हें नौकरी के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार इनसे छेड़छाड़ की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले दिल्ली में १९८५ के मुकाबले १९८६ में छेड़छाड़ की घटनाओं में १७९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

—संयोजन : विनोद मिश्र

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब...

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद, वाह! क्या लाजबाब.......

रश्मि

ज़र्दा

Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
SATYAPAL SHIVKUMAR

सत्यपाल शिवकुमार 60/355, नया बाँस, दिल्ली-110006

(वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

BLISS/DEL

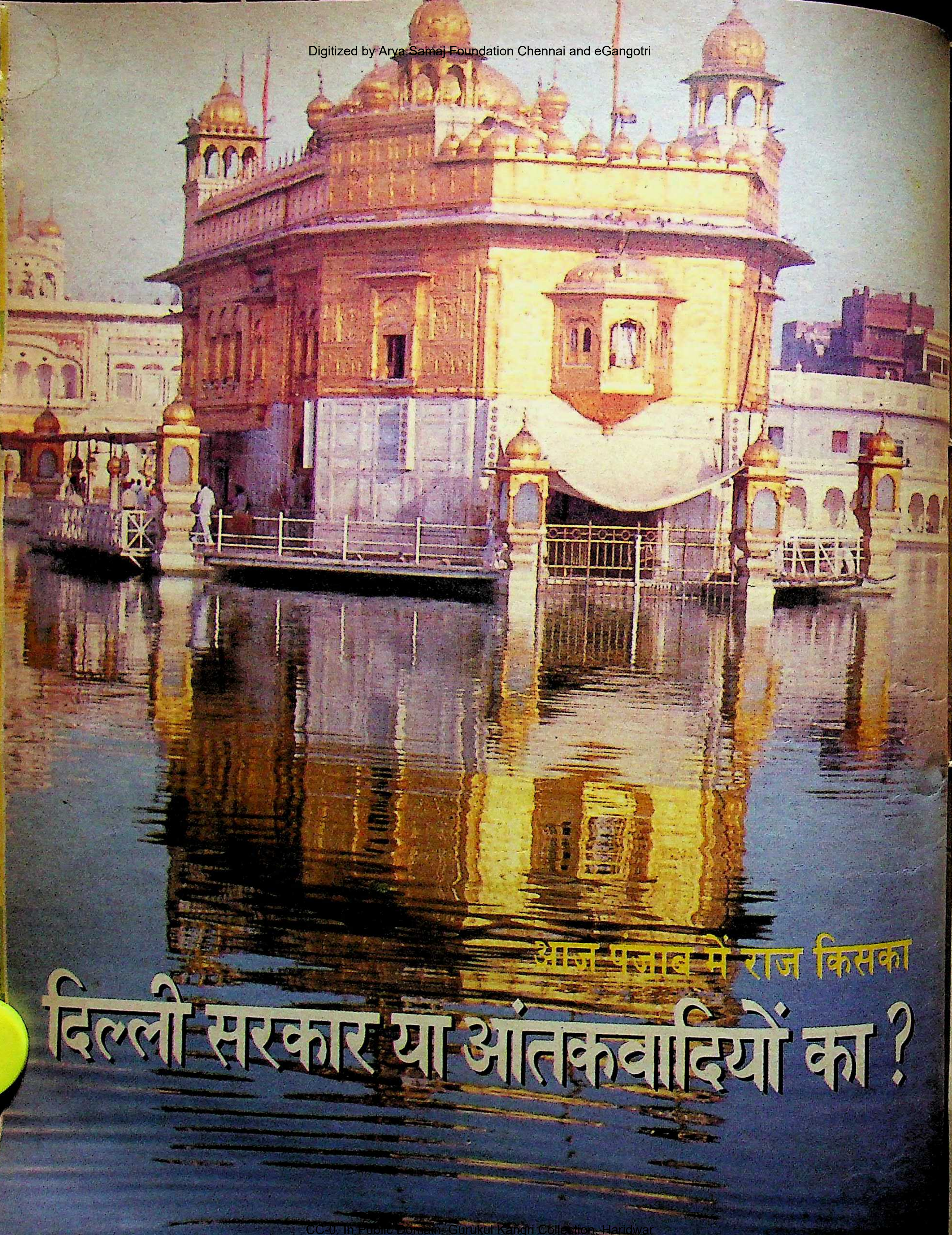

आज पंजाब में राज किसका

दिल्ली सरकार या अंतकवादियों का ?

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बूटा सिंह, पी चिदंबरम और हफ्ते में चार बार उड़कर दिल्ली पहुंचनेवाले पंजाब के राज्यपाल के साथ साउथ ब्लाक में रातें काली करके पंजाब के संदर्भ में जो दो सूत्री रणनीति बनायी थी, उस पर अमल करने के एक माह के भीतर ही भयावह परिणाम निकलने शुरू हो गये हैं। इस रणनीति के तहत भाई जसबीर सिंह को रिहा कर के उन पर भरोसा किया गया था कि वह आतंकवादियों को समझौते की मेज पर लाने के लिए रास्ता हमवार करेंगे। लेकिन १३ अप्रैल को बैसाखी के दिन दमदमा साहिब के सिख सम्मेलन में जो कुछ हुआ है, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि केंद्र ने रोड़े पर जो दांव लगाया था, वह उलटा पड़ गया है। हालत यह हो गयी है कि पंजाब में अब कट्टरपंथ की जगह सशस्त्र विद्रोह ने ले ली है और चार जिलों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन्हीं विद्रोहियों का हुकुम चल रहा है। जिन विद्रोहियों का देश के संविधान, सिख धर्म और सिखों से कुछ लेनादेना नहीं और जो निर्दोष पंजाबियों की हत्या में लगे हैं, क्या उनसे सुलह-समझौता संभव है? क्या ये विद्रोही शत्रु सेना के हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं, ताकि पंजाब में अफरातफरी फैले और शत्रु की मुख्य सेना के नापाक इरादे पूरे हो सकें? पाकिस्तान की व्यूह रचना क्या है और क्या सरकार के पास उसको विफल करने की कोई रणनीति है? पंजाब में नागरिक प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों की स्थिति क्या है? पंजाब की दशा में मार्च से आये गुणात्मक परिवर्तन की आंतरिक रपट व विश्लेषण:

आतंकवादियों के हाथों मां-बाप गंवाकर दादी के साथ स्वर्णमंदिर में न्याय पाने पहुंचा बच्चा

भिंडरांवाले के चरणचिह्नों पर: रोड़े

अमृतसर और फीरोजपुर जिलों के करीब ५० जमींदारों को हुकुम मिला कि वे मांड (बीहड़ इलाका) में 'खालिस्तान कमांडो फोर्स' के सेनापतियों के सामने हाजिर हों। मजबूर जमींदार अपने ट्रैक्टरों-ट्रालियों पर गिरते-पड़ते मांड पहुंचे। वहां उन्हें आदेश मिला कि 'पंथ के भले' के लिए उनमें से प्रत्येक एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक जमा कराये। भयभीत जमींदारों ने योजना बनायी कि इसकी सूचना फीरोजपुर जिले की पुलिस को दे दी जाये, लेकिन इसी बीच अमृतसर जिले में बड़ा जनसंहार हो गया और जमींदारों ने आतंकवादियों को रकम चुका देने में ही अपनी भलाई समझी। यह सरकार पर बंदूकों की विजय थी।

सत्यपाल डांग के अनुसार यह घटना उस दो सूत्री योजना के तीन महीने पहले घटी बतायी जाती है, जिस पर भारत सरकार अमल करने की पहल करने जा रही थी। इस योजना के तहत पहले सरकार को भाई जसबीर सिंह रोड़े (अब अकालतखत के जत्थेदार) तथा अन्य सिख ग्रंथियों को रिहा करना था और फिर उनके जरिये आतंकवादियों को रास्ते पर लाने का काम करना था। यह रणनीति राजीव गांधी, बूटा सिंह, पी चिदंबरम और सिद्धार्थ शंकर राय ने साउथ ब्लाक में रात भर चली बैठकों में तैयार की थी। वास्तव में इन बैठकों से पहली दफा ऐसा लगा था कि केंद्र किसी खास घटना के बाद उसी के संदर्भ में कदम उठाने की लत को छोड़कर, व्यापक परिप्रेक्ष्य में दूरगामी रणनीति बनाने जा रहा है। लेकिन बैठकों में रात काली करके केंद्र ने जो पासा फेंका था और जिस पर विचार करने के लिए हफ्ते में चार बार पंजाब के राज्यपाल दिल्ली उड़कर आते थे, वह उलटा पड गया।

असलियत सामने: १३ अप्रैल को बैसाखी के दिन जो कुछ हुआ, उससे यही सिद्ध होता है। उस दिन रोड़े ने तखत दमदमा साहिब (भटिंडा) में एक विशाल सिख सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें रोड़े ने जो बड़ा निर्णय लिया, वह था—'एआईएसएसएफ' (आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन) के दोनों धड़ों को भंग करके एकता के लिए एक तदर्थ समिति का निर्माण करना।

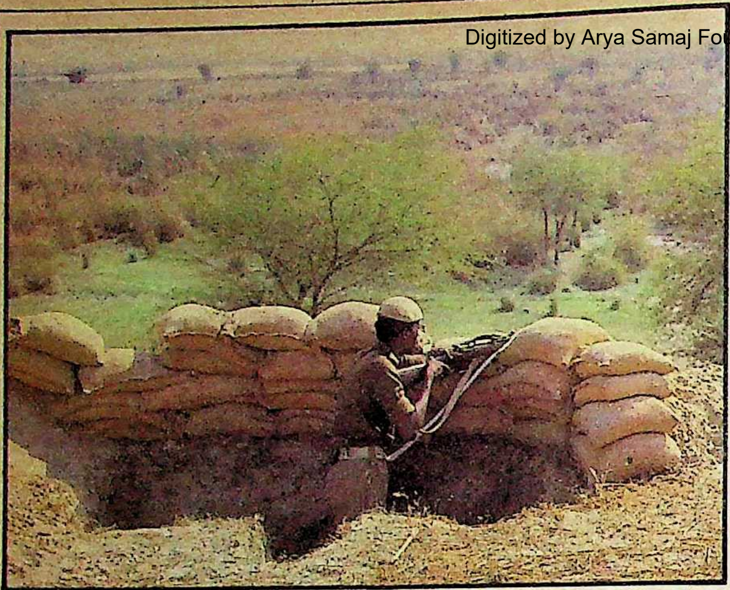

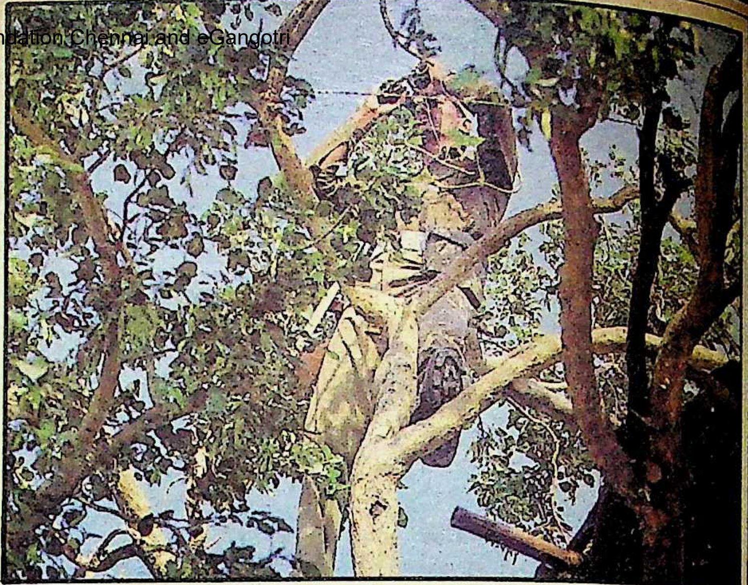

छाया : सुनील सक्सेना

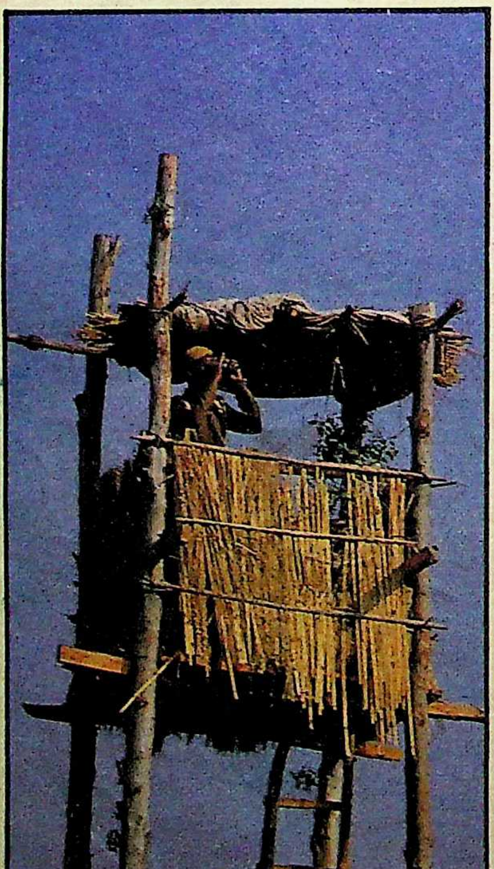

फिर भी आतंकवादी भारी भरकम हथियारों के साथ घुस रहे हैं : सीमा पर चौकसी करते सुरक्षाकर्मी (बायें, दायें और नीचे)

एआईएसएसएफ (अखिल भारतीय सिख छात्र परिसंघ) के धड़ों में से एक का नेतृत्व गुरजीत सिंह कर रहे थे और दूसरे का मनजीत सिंह। गुरजीत सिंह इस समय पाकिस्तान में हैं और मनजीत सिंह जोधपुर जेल में। मार्च में रोड़े के जेल से रिहा होने के बाद से मनजीत सिंह धड़ा उनका समर्थन कर रहा था, जबकि गुरजीत सिंह धड़ा विरोध। लेकिन विडंबना की बात यह है कि रोड़े ने परिसंघ को भंग करके जो तदर्थ समिति बनायी है, उसका अध्यक्ष गुरजीत सिंह को बना दिया है। जाहिर है रोड़े ने ऐसा स्वेच्छा से नहीं किया, बल्कि दबाव में आकर किया है। 'माया' को मिली जानकारी के अनुसार एके—४७ से लैस गुरजीत सिंह के लोग लगातार रोड़े पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ६ मार्च को अकाल तख्त के प्रमुख बनने के दिन जब रोड़े प्रकाश सिंह बादल से मिलने गये, तो ये लोग उनके आस-पास मंडराते हुए उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। जब भी स्वर्ण मंदिर में रोड़े पत्रकारों से मिलते थे, तब भी कान लगाये रहते थे। इससे साफ झलकता है कि न चाहते हुए भी रोड़े को यह स्वीकार करना पड़ा है कि सिख छात्र परिसंघ के पीछे कोई शक्ति है, तो वह है गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह की अनुपस्थिति में उनका 'संदेश' सरबत खालसा में पढ़ा गया और उसके बाद ही रोड़े ने अपने भाषण दिया। जिस समय संदेश पढ़ा जा रहा था, लगभग उसी समय स्वर्ण मंदिर में २०० चक्र गोलियां दागी गयीं। लेकिन इन धमाकों से ज्यादा चिंता का विषय वह है जो गुरजीत सिंह ने अपने 'संदेश' में कहा है। उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कि उनका भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है, कहा, "जो राजनेता सिखों की ओर से संविधान की सीमा में रहकार सरकार से बातचीत करेगा, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। हमें खालिस्तान चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं।" यह केंद्र की उस दो सूत्री रणनीति को सीधी और अशुभ चुनौती है, जिसके तहत वह आतंकवादियों से शांतिपूर्ण समझौते की बाट जो रहा है।

गुरजीत सिंह ने यह भी कहा है, "स्वर्ण मंदिर पर हमला करके इंदिरा गांधी को कीमत चुकानी पड़ी है और पंजाब के राज्यपाल एसएस रे तथा राज्य के पुलिस मुखिया जेएफ रिबेरो की भी वही गति होगी।" अकालियों की भर्त्सना करते हुए गुरजीत सिंह ने उन्हें "कायरों का झुंड बताया है" जो "जून १९८४ में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के समय सरकारी कारों में भाग निकले थे।" साफ है कि रातें काली करके नयी दिल्ली ने जो सपना देखा था, उसे १० मिनट में चकनाचूर कर दिया गया है। जिन रे और रिबेरो पर राजनीतिक समझौते की नींव डालने का जिम्मा था, उनको दंडित करने की धमकी मिल गयी और आतंकवादी अतीत को नजरअंदाज करके जिन रोड़े पर यह आस लगायी थी कि वह आतंकवादियों को रास्ते पर लायेंगे, वह खेमा बदलकर गुरजीत सिंह के साथ लग लिये जो इस समय पाकिस्तान में बैठकर पंजाब में हिंसा का संचालन कर रहे हैं और भारतीय संविधान में जिनका कोई विश्वास नहीं है।

भिंडरांवाले के रास्ते : यदि यह मान भी लिया जाये कि रोड़े ने 'एआईएसएसएफ' में एका स्थापित करने और उसके अतिवादी धड़े का विश्वास प्राप्त करने के लिए गुरजीत सिंह को महत्व दिया है, तो यह बात उनके दूसरे दिन की घोषणा से झूठी साबित हो जाती है। उन्होंने १४ अप्रैल को अचानक घोषणा की कि भाई मनजीत सिंह संयुक्त 'एआईएसएसएफ' के अध्यक्ष होंगे और वह संगठन के चुनावों तक इस पद पर रहेंगे। एका कैसा ? पहले दो धड़ों के दो अलग-अलग अध्यक्ष थे और अब एक तदर्थ समिति का तो दूसरा संयुक्त 'एआईएसएसएफ' का अध्यक्ष है। बात वही है। फिर गुरजीत सिंह के भाषण के बाद उन्होंने जो कुछ कहा है, उसमें यद्यपि खालिस्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन

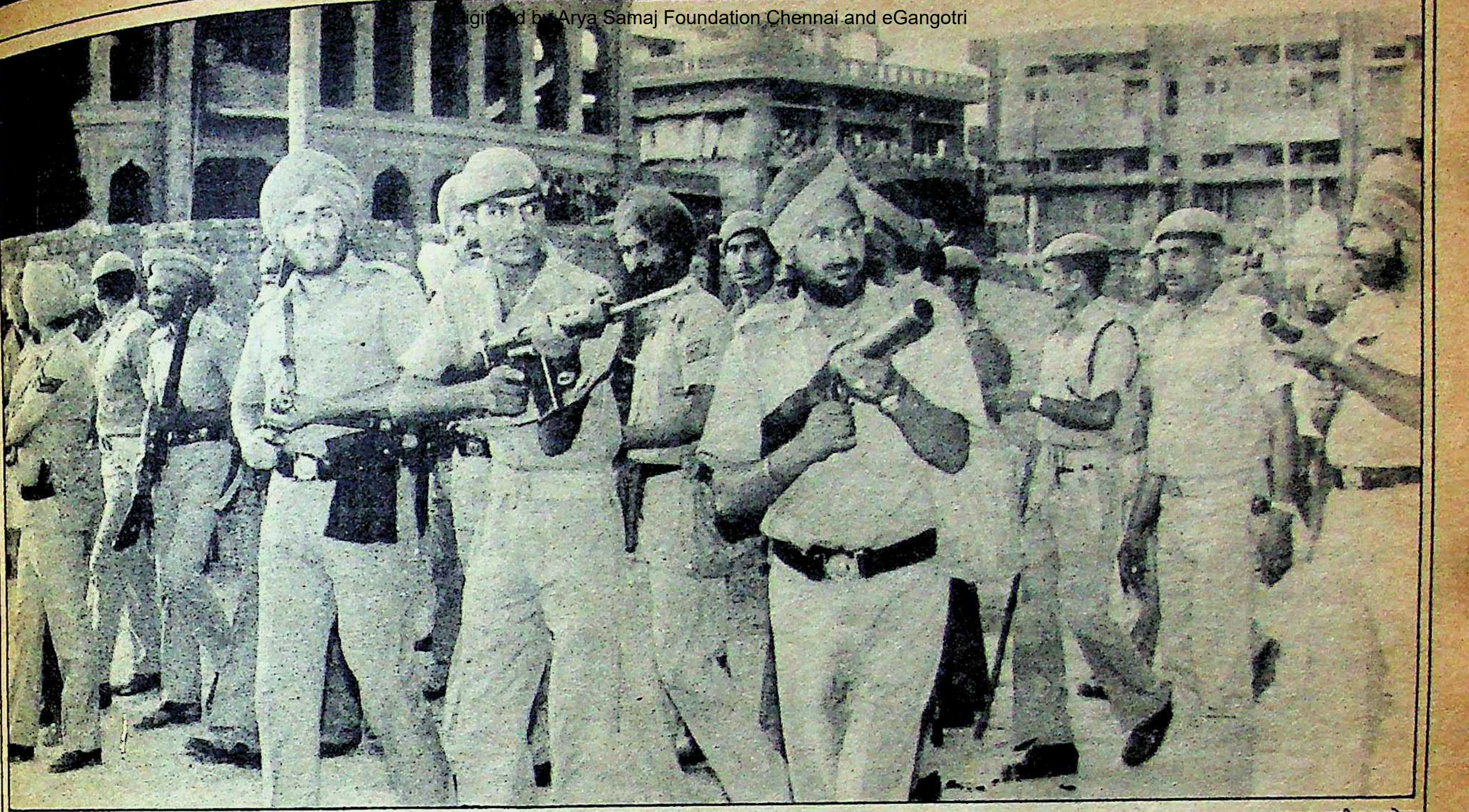

फिर भी आतंकवादी हावी : पंजाब में ऐसे दृश्य आम हैं

छाया : सुनील सक्सेना

शब्द वही हैं जो उनके चाचा भिंडरांवाले इस्तेमाल किया करते थे। स्मरणीय है कि भाई जसबीर सिंह, भिंडरांवाले के पिता बाबा जोगिंदर सिंह की पहली पत्नी से जन्मे जागीर सिंह के पुत्र हैं। रोड़े ने दमदमा साहिब में कहा है, "शहीदों की कुर्बानी किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पंथ के लिए होती है...सिखों के साथ भारत में इसलिए भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वे सिख हैं।" इसी तरह की बातें कहकर भिंडरांवाले अपने अनुयायियों को उत्तेजित किया करते थे, जिसकी दुखद परिणति १९८४ के 'ब्ल्यू स्टार' में हुई थी।

बलदेव प्रकाश और सत्यपाल डांग जैसे नेताओं की चेतावनी को यह कह कर नजरअंदाज किया जा सकता है कि वे दलगत सिद्धांतवादी हैं, लेकिन पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि १३ अप्रैल के बाद रोड़े के पास भिंडरांवाले का लघु संस्करण बनने के सिवा कोई चारा नहीं है। इन पुलिस अधिकारियों का विश्लेषण है कि रोड़े की गतिविधियों और भाषणों पर लाभ सिंह, अवतार सिंह ब्रह्मा और गुरजीत सिंह जैसे छंटे हुए आतंकवादियों का नियंत्रण रहेगा। अवतार सिंह इस समय मांड में कहीं छिपे हुए हैं और लाभ सिंह तथा गुरजीत सिंह पाकिस्तान में बताये जाते हैं।

उलटी नीतियां : शुरू में दी गयी मांड की घटना को देखते हुए पंजाब की आज असलियत यह है कि लोग आतंकवादियों की दया पर जिंदा हैं। किसी को यह विश्वास नहीं है कि केंद्र कुछ कर सकता है या रे संचालित राज्य सरकार उनकी रक्षा कर सकती है (देखिए लुंजपुंज प्रशासन कथा)। निर्णय कैसे लिये जाते हैं, इसकी मिसाल है दमदमी टकसाल से संबद्ध भाई मोखम सिंह की रिहाई। सुरक्षा बलों ने उनकी रिहाई का विरोध किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गयी। १३ अप्रैल को सिख सम्मेलन में मोखम भी बोले थे। उन्होंने फरमाया, "आजादी हमारा अधिकार है...सिखों में फूट होने के कारण दिल्ली के हिंदू शासकों ने हमें गुलाम बनाये रखा है।" उन्होंने सिखों को अलग कौम बताते हुए कहा, "हम हिंदू नहीं हैं और सारा जहान जानता है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।"

जिस व्यक्ति पर केंद्र ने दांव लगाया और सुशील मुनि के कहने पर जिसे विश्वास का आधार बनाया, आज वही व्यक्ति 'रोड़े' रिहा होने के एक माह के भीतर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे सीखने में भिंडरांवाले को कुछ साल लगे थे। रोड़े के सामने मोखम सिंह ने खालिस्तान का आह्वान किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। गुरजीत सिंह के देशद्रोही संदेश को उन्होंने पढ़वाया ही नहीं, बल्कि गुरजीत सिंह को 'एआईएसएसएफ' की कमान भी सौंप दी।

केंद्र जिस तरह से निर्णय लेता है, उसका यही परिणाम होना था। पंजाब के जाने-माने प्रेक्षक पत्रकार राजेंद्र सरीन का मानना है, "जिन सुशील मुनि को बीचबचाव करने के लिए केंद्र ने चुना, वह राजनीतिक जटिलताओं से नावाकिफ हैं। सभी जानते हैं कि वह एक भोलेभाले और नेक इंसान हैं। दूसरे संधि विग्राहक थे, स्वर्गीय तरलोचन सिंह रियासती, जिनको अपनी जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा, क्योंकि उन्हें आतंकवादी यह मानते थे कि वह 'सिखों को सस्ते में बेच रहे थे'। दर्शन सिंह रागी इसलिए अप्रासंगिक बन गये, क्योंकि सुशील मुनि ने उनसे बातचीत करके समझौते की जो रूपरेखा बनायी थी, उसको केंद्र ने बिना कारण बताये रद्द कर दिया।"

दरअसल, छत्तीस नीम-हकीमों के नुस्खे आजमाने के लिए छोड़े गये मरीज की जो नियति होती है, वही हालत आज पंजाब की है। केंद्र को रोड़े को छोड़ने की नीति अपनाने की सलाह इसलिए दी गयी थी कि वह अपनी आतंकवादी पृष्ठभूमि की बदौलत लाभ सिंह और गुरजीत सिंह जैसे छंटे हुए आतंकवादियों को अपने प्रभाव में लेने में समर्थ हो सकेंगे। केंद्र ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि रोड़े तथा अन्य को जोधपुर जेल भेज देने के बाद गुरजीत सिंह जैसे लोग पाकिस्तान के 'आतंकवादी राजदूत' बन बैठे थे और अमरीका तथा ब्रिटेन में रहनेवाले अतिवादी सिख कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाब का मसला हल हो।

सशस्त्र विद्रोह : आज पंजाब का नंगा सत्य और अहम मसला यह है कि वहां सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है और जिसका संचालन सीमा पार से हो रहा है। रिहा होने के बाद अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके जब बादल आतंकवादियों को किसी समझौते की ओर मोड़ने के अपने वादे को पूरा नहीं कर सके थे, तो केंद्र को रोड़े, कश्मीरा सिंह तथा दूसरों को रिहा करते समय दो बार सोचना चाहिए था। बादल ने पुलिस अत्याचार की मनगढ़ंत

साक्षात्कार/**किशोर चन्द्र**

'हमारा तो किसी पर भरोसा ही नहीं रह गया है'

बहुत दिनों तक अमृतसर पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके और अत्यधिक आक्रामक हिंदू नेता पंडित किशोर चंद्र के घर पर सुबह-शाम व्यथित, उत्पीड़ित परिवार सहायता की गुहार लेकर पहुंचते रहते हैं। शिवसेना अध्यक्ष किशोर चन्द्र की बुलंद आवाज और तेज चलने की आदत से यह नहीं लगता कि वह साठ बसन्त देख चुके होंगे। उनकी जान को खतरा है। अमृतसर में आंतकवादियों की हिट-लिस्ट में वह सर्वोपरि हैं। किंतु वह प्रायः अपनी सफेद जिप्सी पर अपने अंगरक्षकों सहित सवार होकर बेधड़क घूमते हैं। जहां भी हत्याकाण्ड होता है, वह अपनी विशेष राइफल .४६५ के साथ उत्पीड़ित परिवार को ढाढ़स देने पहुंच जाते हैं। बहुतेरे पंडितजी को कट्टर सांप्रदायिक करार देते हैं, किंतु उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पंजाब संबंधी अपने विशिष्ट विचारों के साथ उन्होंने 'माया' से जो विस्तृत बातचीत की उसके प्रमुख अंश:

माया: बाहर से जो हथियार आते हैं, वह क्या तस्कर लाते हैं?

चन्द्र: हां, ये तस्कर लाते हैं और आतंकवादियों को देते हैं। इस प्रकार उन हथियारों से हिंदुओं को मारते हैं। जो जितने अधिक कत्ल करता है, उसे ले० जनरल या जनरल का खिताब देते हैं। मैं हाल में तरनतारन के गोविंदवाल और फतेहाबाद के इलाकों में गया था। वहां सैकड़ों सिख परिवार हैं, किंतु मुश्किल से ६-७ हिंदू परिवार हैं। अधिकांश हिंदू परिवारों को या तो भगा दिया गया है या कत्ल कर दिया गया है। लाभ सिंह जैसे मामूली इंसान को अनेक कत्ल करने के एवज में जनरल बना दिया गया। हाल में हत्याओं में आयी बाढ़ की एक वजह केन्द्र सरकार की नरमी है। बादल जैसे उग्रपंथी नेताओं को रिहा करना सरासर गलत है। इनके खून में यह बात मौजूद है कि ये बदलेंगे नहीं। लूटमार करना जिनकी आदत बन गयी है, वे क्या प्यार की भाषा समझेंगे। १३ साल की एक हिंदू लड़की ने मुझे बताया कि वह हरमंदिर साहिब में १० साल की उम्र से काम कर रही थी। एक दिन वह अंदर दर्शन करने गयी, वहां उसे खींच कर एक कमरे में ले जाया गया था। फिर ३ साल से अनेक नौजवान उसकी इज्जत लूटते रहे थे। इस अबोध लड़की की इज्जत लूटने के साथ-साथ वे उससे हथियारों को इधर-से-उधर पहुंचाने का भी काम करा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र की बच्ची पर हथियार ले जाते समय कोई क्या शक करेगा?

माया: क्या उस लड़की को पकड़ लिया गया?

चन्द्र: हां, उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसके माता-पिता को बुलाकर कहा कि अपनी बच्ची को ले जाओ। माता-पिता ने कहा कि हम इसे नहीं ले जायेंगे, यह अब हमारे किसी काम की नहीं है। क्या इसीलिए हमारे हिंदुओं ने हरमंदिर साहिब को बनाया था? दरअसल, इस मंदिर का असली नाम हरिमंदिर था और इसे बनाने और नामकरण करनेवाले हिंदू ही थे। १९८१ में हमने जुलूस निकाला था और नारा लगाया था कि हरिमंदिर हमारा है। अकाल तख्त भी हिंदुओं का बनाया हुआ था और गुरु हरि गोविंद को हिंदुओं ने बनाकर दिया था। गुरु गोविंद सिंह पक्के हिंदू थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 'सकल जगत में खालसा पंत जागे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भागे'। अर्थात अगर खालसा पंथ जागता रहेगा, तो हिंदू धर्म जगेगा और पाखंड दूर हो जायेंगे। मास्टर तारा सिंह की लड़की राजिन्दर कौर ने १९८३ में हरमंदिर के सामने कहा था कि अगर हिंदुओं ने सिगरेट-बीड़ी पीनी बंद नहीं की, तो हम गो-मांस खायेंगे। मैंने इसका जवाब देते हुए पूछा था कि राजिन्दर कौर खुद किसी गुरु की सिखनी है? कारण खुद गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 'ऐ भगवती ऐ दुर्गा यदि आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं तुर्कों का नाश कर दूं, जिससे गउओं का नाश करनेवाले हमेशा के लिए खतम हो जायें।' तमाम गुरुओं के कामकाज में हिंदू पद्धतियों का पालन किया जाता था। जब गुरु हरगोविंद का शगुन आया, तो उन्होंने पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। फिर गुरु हरगोविंद को चौकी पर बैठाकर स्नान कराया गया, नये कपड़े पहनाये गये और यज्ञोपवीत किया गया, फिर गणेश पूजा करायी गयी। यह सब मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि ये सारी बातें दरबार साहिब की हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुओं ने सिखों के प्रति भी अत्यधिक कुर्बानियां की हैं। जब गुरु तेग बहादुर का चांदनी चौक (दिल्ली) में औरंगजेब ने शीश कटवाया, तो वहां पहुंचे बहुत से लोगों में सबसे आगे थे भाई मतिदास। भाई मतिदास को भी खड़ा करके आरे से चीर दिया गया था। फिर भाई सतीदास को नंगा करके उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाते थे और अंग-अंग नोचते थे। वह भी शहीद हो गये। तीसरे प्रतिज्ञा भाई दयालजी थे। उनको खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। उसके बाद मौजूद सब लोग भाग गये। यह सारी बातें भी दरबार साहिब में लिखी हैं। इतनी कुर्बानियां देनेवाले हिंदुओं को आज वही सिख मार रहे हैं। गुरु साहिब ने फरमाया था कि यहां म्लेच्छ राज्य पैदा होगा जो सिखी का बेड़ा गर्क करेगा। यह वही म्लेच्छ लोग हैं जो गुरु साहिब के कथन को सच्चा सिद्ध कर रहे हैं। जो अधिक कत्ल करता है, उसे दरबार साहिब मंदिर में ले जाकर बैठा देते हैं और वह अकाल तख्त का महंत बन जाता है। एक लुटेरे कातिल को इतना सम्मान देना बहुत बड़ी गलती है।

माया: ऐसा क्यों किया जा रहा है?

चन्द्र: ये ऐसे लोग हैं कि इन पर हुकूमत सबसे ज्यादा मजबूत आदमी ही करता है। जो थानेदार बदमाशों को ज्यादा जूते मारता है, वे बदमाश उससे डरते हैं और इलाका छोड़कर चले जाते हैं। अपराधियों के दिमाग में अगर यह बैठ गया है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो वे नंगा नाच तो करेंगे ही। मैं दावे से कह सकता हूं कि यहां लाखों-करोड़ों रुपए सिख पुलिस बना रही है। और किनसे? आतंकवादियों से। हम १९८२ से चिल्ला रहे हैं कि हिंदू पुलिस बहुत कम है। उस समय युवराज कर्ण सिंह ने मुझसे पूछा था कि पंजाब का हाल क्या है? मैंने जवाब दिया था कि जितने हथियार उनके पास हैं, उतने हथियार हमें दे दीजिए, तो हम 'खालिस्तानियों' का नामोनिशान मिटा देंगे। मैंने उस समय हिंदू नौजवान दल बनाया था, आतंकवादियों के खिलाफ। किंतु हमारी कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमे बनाये और मेरे नौजवानों को झूठे मामलों आदि में फंसाकर बुरी तरह आतंकित किया। इससे हमारा जोश खतम हुआ। अगर ऐसा न हुआ होता, तो केन्द्र को आज यहां सीआरपीएफ आदि को भेजने की

जरूरत न पड़ती। हम देश की एकता और अखंडता के समर्थक हैं और ये आतंकवादी देश के दुश्मन हैं। हमने कहा था कि पंजाब में शांति चाहते हो, तो हिंदुओं को मजबूत कर दो। आज एक हजार चीनी राइफलें और ७०० लोग (आतंकवादी) स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद हैं और एक-एक के पास दो-दो तीन-तीन हथियार हैं। यह खबर एक सिख ने ही आकर दी थी। यदि इस ओर ध्यान न दिया गया, तो ये लोग हज़ारों की तादाद में हथियार लेकर निकलेंगे और सार्वजनिक रूप से कत्लेआम करेंगे।

माया: सरकार का कहना है कि यदि हम उग्रपंथियों से समझौता-वार्ता नहीं करेंगे, तो मसला कैसे हल होगा, क्योंकि और सारे प्रयास, मसलन बरनाला सरकार, विफल रही है।

चन्द्र: जो खालिस्तान बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या वे इनकी बात सुनेंगे। रोड़े कहेंगे कि फ्लां-फ्लां आतंकवादी गुट हमारा कहना नहीं मानता। यह सब इनकी साजिश है। ये पागल लोग हैं। मैंने सुशील मुनि के यहां आने पर उनसे कहा था कि यदि आप इन लोगों को रिहा करा देंगे, तो पछतायेंगे। मैंने बरनाला से भी कहा था, "इनके छोड़ने से पहले इन्हें गुरुबानी पढ़ाओ-समझाओ तब कहीं जाकर इनका रंग बदलेगा। आपने तो डकैतों को छुड़ाकर फिर ड़कैती करानी शुरू करवा दी है।" रिहाई के बाद उन्हें बिना सूद के कर्जे, मिनी बस आदि जीवनयापन के लिए दी गयी, किंतु हम बेकुसूर हिंदुओं को तो महज खोना ही है। हमारी तो जान भी सुरक्षित नहीं।

> **हिंदुओं ने सिखों के प्रति भी अत्यधिक कुर्बानियां की हैं। कुर्बानियां देनेवाले हिंदुओं को आज वही सिख मार रहे हैं। गुरु साहिब ने फरमाया था कि यहां म्लेच्छ राज्य पैदा होगा जो सिखी का बेड़ा गर्क करेगा। यह वही म्लेच्छ लोग हैं जो गुरु साहिब के कथन को सच्चा सिद्ध कर रहे हैं। जो अधिक कत्ल करता है, उसे दरबार साहिब मंदिर में ले जाकर बैठा देते हैं और वह अकालतख्त का महंत बन जाता है। एक लुटेरे कातिल को इतना सम्मान देना बड़ी गलती है।**

माया: अब सिख, सिख को क्यों मार रहा है?

चन्द्र: अकसर जमीन-जायदाद के झगड़े में पैसे देकर लोग कत्ल करा रहे हैं। ऐसी हत्याएं ज्यादातर व्यक्तिगत दुश्मनियों के कारण की जाती हैं। इसके अलावा जो आतंकवादियों को समझाता-बुझाता है या पैसा, हथियार या शरण देने से इनकार कर देता है, तो वह उसकी हत्या कर देते हैं।

माया: आतंकवादी राकेट कैसे ले आये?

चन्द्र: ये या तो सिर पर या ट्रकों पर लादकर राकेट लाते हैं। पहले तो सीआरपीएफ वाले मुस्तैद थे, पर अब वह भी पैसा कमाने में लग गये हैं, इसके मेरे पास सबूत हैं।

माया: रिबेरो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

चन्द्र: रिबेरो साहब का यह काम ठीक नहीं था जो उन्होंने गांवों में जाकर कहा कि अपने लड़कों को पुलिस में भर्ती करो। वही आदमी अक्लमंद है जो दूरदेश हो। मैंने जब भर्ती का विरोध किया, तो जवाब मिला कि इससे पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेनेवालों की संख्या कम हो जायेगी। मैंने कहा कि वे बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान जायेंगे। वह आपसे ही ट्रेनिंग लेंगे, पैसा लेंगे और हथियार लेंगे और आपको मारेंगे।

माया: राज्यपाल रे क्या मसले का हल कर रहे हैं?

चन्द्र: उनकी खुशामद करने की आदत मुझे पसंद नहीं है। उन्हें तो कहना चाहिए कि जिन गांवों में कत्ल हुआ है, उसकी तमाम पंचायत को हम दोषी मानेंगे। मैंने तो उन्हें सलाह दी थी कि वह हर कौम के ८-१० देशभक्त लोगों की टोलियां हर गांव में सुरक्षा समितियों के रूप में तैयार करायें, किंतु इस पर अमल नहीं हुआ। देशभक्त लोगों को हथियार भी देना चाहिए। धनी सिखों के पास हथियार हैं जो ज्यादातर या तो आतंकवादियों के समर्थक हैं या तटस्थ। जो देशभक्त गरीब हिंदू हैं और देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वे निहत्थे हैं।

माया: स्वर्ण मंदिर की जो आज स्थिति है, क्या पहले कभी थी?

चन्द्र: आपरेशन ब्ल्यू स्टार के पहले जिस प्रकार स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों और हथियारों का गढ़ बन गया था, वही हालत आज पुन: बन गयी है। मुझे पता चला है कि बिहार से पंजाब में मजदूरी करने आये लगभग १०० लोगों को वहां जबरन रोक रखा गया है और उनसे गड्ढे और खाइयां खोदवाई जा रही हैं। मेरी सूचना के अनुसार अब ६०० आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में उपस्थित हैं। उनकी तैयारी आपरेशन ब्ल्यू स्टार के समय से भी अधिक है। ■

कहानियां सुना-सुनाकर आतंकवादियों का विश्वास पाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वह चार बार अमृतसर से खाली हाथ लौट आये। वह स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों से संपर्क करने में असमर्थ रहे।

बादल की वादाखिलाफी के बाद यह कहा जाता है कि रिबेरो इस हक में नहीं थे कि आतंकवादियों से नरमी से पेश आया जाये और रोड़े तथा मोखम सिंह जैसे लोगों को छोड़ा जाये। यहां तक कि बूटा सिंह के बारे में भी यह कहा जाता है कि वह सुरक्षा बलों की सख्ती जारी रखने के हिमायती थे। लेकिन सुशील मुनि, पी चिदंबरम और पंजाब के जाट सिख नेताओं ने राजीव गांधी को मंत्र दिया कि वह आतंकवादियों से शांति का सौदा करने की कोशिश करें और यह काम रोड़े जैसे व्यक्तियों को छोड़नें से ही हो सकता है, जिनकी गिरफ्तारी पर सरकार के लगभग एक करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रोड़े का खालिस्तानी खेमे में जाने का यदि सरकार को अंदाज नहीं था, तो कम-से-कम यह तो पता हो ही जाना चाहिए था कि सरकार की रणनीति साकार करने में वह सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आतंकवादी पूर्णतया सशस्त्र राजद्रोही हो गये हैं और इसका ऐलान वे अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रदर्शन करके कर रहे हैं। यह भी पता होना चाहिए था कि आम पंजाबियों का प्रशासन से विश्वास उठ गया है और रोड़े आतंकवादियों के सामने नहीं ठहर पायेंगे, क्योंकि उन पर उन्हीं पाक आकाओं का हाथ है, जिनका कभी रोड़े पर भी होता था।

हताशा: पंजाब में किस तरह की हताशा व्याप्त है, इसकी मिसाल उस समय मिली, जिस समय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी चिदंबरम जिला स्तर पर बैठकें करके जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों से हालात की जानकारी हासिल कर रहे थे। उस समय बगल के कमरे में राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे को पत्रकारों ने घेर रखा था। जब रे ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास समाधान है, तो पत्रकारों ने कहा कि उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? रे का जवाब था कि इसे समय पर खोला जायेगा। इस पर कुछ पत्रकारों ने टिप्पणी की, "उम्मीद है, तब तक हम जिंदा रहेंगे।" यह टिप्पणी पंजाब के लोगों की आशाओं के औंधे पड़े घड़ों की प्रतीक है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि १९८८ के शुरू होने के साथ जब से केंद्र की पंजाब में नयी नीति का उदय हुआ है, तब से प्रतिदिन औसतन आठ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है।

बैसाखी के पहले भी अमृतसर का कोई सिख आशावान नहीं था कि रोड़े कुछ सुखद परिवर्तन ला सकेंगे। इसके बावजूद केंद्र उन पर अपने विश्वास का दबाव बढ़ाता रहा और सुरक्षा बलों को धीरज रखने का उपदेश देता रहा। यहां तक कि कोहना देसियां (जालंधर) लोहड़का और खीरांवाली (कपूरथला) तथा पट्टी (अमृतसर) में मात्र एक-एक घटना में क्रमश: १८, ३७ और ४५ लोगों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी रहने के बावजूद केंद्र को यह होश नहीं आया कि

क्या ये शांति के रास्ते हैं? : बंदूकें दाग कर रोड़े का स्वागत

छाया: सुनील सक्सेना

आतंकवादियों से नरमी बरतने से काम नहीं चलेगा। आतंकवादियों द्वारा राकेट दागने पर भी केंद्र की नींद नहीं टूटी, क्योंकि उसे १३ अप्रैल को कोई चमत्कार होने की उम्मीद थी।

चेतावनी: एक सप्ताह पहले डांग ने चेताया था, "ग्रंथी और रोड़े क्या कर सकते हैं? उनकी यह तक कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि मासूम लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए।" बादल तथा दूसरों ने जो कहा भी है, तो यह कि मारकाट के पीछे वे लोग हैं जो सिखों को बदनाम करना चाहते हैं। असली बात यह है कि अकाली हों या ग्रंथी, वे वही बोलते हैं, जो आतंकवादी बंदूकों के बल पर उनसे बुलवाना चाहते हैं। यह स्थिति तभी टाली जा सकती थी, जब सुरक्षाकर्मियों को आतंकवादियों को कुचलने की इजाजत मिलती। आतंकवादियों को हिम्मत जुटाने की मोहलत देने का ही यह नतीजा है कि रोड़े को सरकार का परोक्ष समर्थन मिलने के बावजूद वह 'सिखों की आजादी' से कम मांग करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।

इतिहास की पुनरावृत्ति: १३ अप्रैल को चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन नये भिंडरांवाले के पैदा होने के आसार पैदा हो गये हैं और कुछ देश द्रोहियों को वैधता मिल गयी है। उन नौजवानों को अगुवा गुरजीत सिंह बन गये हैं, जिनमें से आतंकवादियों की भरती की जाती है। इतिहास फिर अपने को दुहराने लगा है।

पहले अकालियों को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने संत फतेह सिंह को उभारा था जो आगे चलकर काबू के बाहर हो गये थे। इसके बाद भिंडरांवाले को तैयार किया। जब वह बहुत शक्तिशाली बन गये, तो उनको फुसलाने की अकालियों ने भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, "मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कांग्रेसियों का भी और अकालियों का भी।" डांग तो बादल की रिहाई की तुलना भिंडरांवाले की रिहाई से करते हैं। डांग महसूस करते हैं कि जिस दिन से बादल रिहा हुए हैं, उस दिन से हालात ज्यादा खराब होने शुरू हो गये। रोड़े आदि को आजाद करने के बाद स्थिति और गंभीर हो गयी है। ऐसी स्थिति में केंद्र के लिए इंतजार करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन पिछले तीन खूनी महीनों में केंद्र ने केवल इंतजार ही तो किया है।

आपातकाल भी निरर्थक: ५९वें संशोधन से केंद्र ने आपातकाल का जो हथियार हाथ में लिया है, वह भी निरर्थक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को दहशत फैलाने की छूट दी जा रही है और उनको भय पैदा करने की चाबी हाथ लग गयी है, जबकि यह चाबी रे और रिबेरो के पास होनी चाहिए थी। यदि रे और रिबेरो हावी होते, तो मोखम सिंह और रोड़े उस भाषा में बात नहीं करते, जिसमें वह कर रहे हैं।

दरअसल, केंद्र चेतावनी के संकेतों को समझने में विफल रहा है या उनको अनदेखा किया है। जिस दिन रोड़े रिहा हुए, उस दिन स्वर्ण मंदिर से ४०-५० आतंकवादी बाहर आये और गोलियां दाग कर उन्होंने अपनी विजय के उल्लास का प्रदर्शन किया था। उनके धन ऐंठने, हत्याएं करने का क्रम जारी था और रोड़े दरबार साहिब में विचार-विमर्श में मशगूल थे।

आतंकवादियों को नये-नये हथियार जुटाने का क्रम जारी रहा और रोड़े तथा अन्य लोग इस क्रम को नहीं रोके सके। यह भी स्पष्ट हो गया कि बादल, अमरिंदर सिंह, बरनाला आदि सभी अकाली नेता अप्रासंगिक हो गये हैं। पंजाब में मार्च से केवल एक ही भाषा और राजनीति शुरू हुई है, वह है बंदूक।

२८ मार्च को दिल्ली के हैदराबाद भवन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलायी थी, जिसमें अश्विनी मिन्ना और सत्यपाल डांग भी शामिल थे। इस बैठक में तीन सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ़ सख्त कदम उठाये जायें और रोड़े से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए तथा १३ अप्रैल तक 'आम माफी' जैसी स्थिति न बनाये रखनी चाहिए।

डांग कहते हैं, "इमरजेंसी के बारे में मेरी राय स्पष्ट है। मान लीजिए मैं किसी रोग से ग्रस्त हूं और आपके पास उसकी दवा है। लेकिन आप उसे तब तक नहीं देते हैं, जब तक मेरा मर्ज बढ़ कर ऐसा न हो जाये कि उसके लिए ऐसी बड़ी दवा देनी पड़े, जिससे दूसरे रोग खड़े हो सकते हैं। इमरजेंसी कुछ ऐसी ही चीज है।" डांग का मत है कि यदि हालात को इसी तरह बिगड़ने दिया गया, तो इमरजेंसी लाजमी हो सकती है। लेकिन उस समय ऐसी कार्रवाई के गंभीर कुपरिणाम निकलेंगे। यह बात सही है। जब डीआईजी अटवाल मारे गये थे, तो गुरुनानक निवास से भिंडरांवाले की गिरफ्तारी न करने का परिणाम आगे चलकर यह हुआ कि

बेगुनाहों की निर्मम हत्या

छाया: राना जसपाल सिंह

पंजाब अब विधवाओं का प्रदेश : रैली में बिलखती विधवा

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' की नौबत आयी। उसी तरह की स्थिति अब होती जा रही है।

केंद्र को इस बात का अहसास होना चाहिए था कि हरित क्रांति के बाद जो धनी जमीदार और धनी हुए हैं वे राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बनने की लगातर कोशिश करते आ रहे हैं। वे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस व अन्य अकालियों से सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनकी मदद वे लोग भी करते आ रहे हैं जो विदेशों में हैं। इस प्रकार यहां रहने वाले और बाहर जाने वाले सिखों के बीच सत्ता पाने की दृष्टि से एक संबंध है। जब ये राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए धर्म को जोड़ते हैं, तो खालसा राज्य की धारणा स्वतः ही उभर कर आ जाती है। 'खालसा का बोलबाला' का वास्तविक मतलब है एक धार्मिक राज्य जो शुरू में सिख भारत में ही चाहते ते। जब वे ऐसा करने में विफल रहे, तो नौजवानों में धर्म और जाति की भावनाओं के बीज बोने शुरू कर दिये, जिससे छोटी-छोटी घटनाएं होने लगीं। बेरोजगारी ने इन हालात की आग में घी का काम किया। आज वही वर्ग आतंकवादियों के रूप में उभर कर सामने आ गया है।

एक अध्ययन के अनुसार अमृतसर जिले के ४०-५० आतंकवादी हत्यारों में से केवल एक खेतिहर मजदूर वर्ग का था। इस वर्ग के लोग अब भी आतंकवादियों के विरोधी हैं। वे सिख ही हैं, लेकिन खुले में विरोध करते हुए डरते हैं। इसी तरह सिखों में २०-२५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं और वे भी आतंकवाद के विरोधी हैं। एक कारण यह भी है कि बूटा सिंह आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के पक्षधर हैं। लेकिन जिनका प्रधानमंत्री पर ज्यादा प्रभाव है, उनके सामने बूटा सिंह की नहीं चल पा रही।

वैसे चंडीगढ़ के सरकारी तंत्र ने ऐसी धारणा फैला रखी है कि पंजाब में आज जो संकट है, उसका मूल कारण बूटा सिंह ही हैं। जाहिर है कुछ लोग परदे के पीछे रह कर हर कीमत पर शांति स्थापित करने का श्रेय लूटने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं।

हरावल दस्ता : लेकिन पासे गलत पड़ चुके हैं। अब आतंकवादी न धार्मिक कट्टरपंथी हैं और न उनकी कमान भिडरांवाले संभाले हैं। अब वे ऐसे हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जनता के सामान्य जीवन को भंग करके उसमें दहशत फैलाना है, ताकि मुख्य सेना आकर क्षेत्र पर कब्जा कर ले। इसी कारण अब वह खालिस्तान का ऐसा नक्शा लिये घूम रहे हैं, जिसमें सारे भारत को 'खालिस्तान' के रूप में दिखाया गया है। कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा रखा है और दिल्ली को सतवंत नगर तथा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को बेअंत सिंह हवाई अड्डे का नाम दे रखा है। इससे बढ़ कर राजद्रोह और क्या हो सकता है?

ऐसी स्थिति में केंद्र को यह महसूस होना चाहिए कि रोड़े, रे और रिबेरो तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक आतंकवादियों के साथ शत्रु की सेना जैसा व्यवहार नहीं होता और उनको समझौते की मेज पर लाने के बजाय, समर्पण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। भारत ढाका में तभी पहुंचा था, जब जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेना को पराजित किया था।

पंजाब में भी भारत सिखों या सिख आतंकवादियों के खिलाफ नहीं; बल्कि शत्रु सेना के साथ लड़ रहा है, जहां चार जिलों में रे की नहीं, आतंकवादियों की सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में उनसे शांति समझौता कैसा? अब वक्त आ गया है कि मुनियों और साधुओं के जरिये आतंकवादियों को मनाने के बजाय केंद्र कोई ठोस रणनीति अपनाये। जो बंदूकों की भाषा में बात करते हैं, उनको बंदूकों से ही चुप किया जा सकता है।

—विजयदत्त ब्यूरो रिपोर्ट के साथ

तीन मास में
२६५ सिखों की हत्या

सिख, सिख ही को क्यों मार रहा है?

पंजाब में चल रही मारकाट ने इस वर्ष १३ अप्रैल को बैसाखी के दिन एक दशक पूरा कर लिया है। दस वर्ष पूर्व १९७८ में इसी बैसाखी के दिन अमृतसर के रेलवे स्टेडियम में भिडरांवाले के साथियों और निरंकारियों में खूनी झड़प हुई थी और १७ लाशें बिछ गयी थीं, जिनमें १३ लाशें भिडरांवाले के साथियों की थीं। लेकिन आज जिस मात्रा में पंजाब में खून बहाया जा रहा है, उसके सामने दस वर्ष पूर्व हुआ उक्त रक्तपात बहुत मामूली नजर आता है। उस समय तलवार, भाला और छुरे जैसे पारंपरिक हथियारों से रक्त बहा था और लड़ाई का उद्देश्य धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करना था, लेकिन आज पृथक खालिस्तान के लिए पजाब में हत्याएं हो रही हैं और हत्यारे एके-४७ रायफल और आरपीजी राकेटों जैसे अत्याधुनिक हथियारों से ~~हिंदू-सिख, औरत-मर्द,~~ बच्चे-बूढ़े या जवान—किसी में कोई फर्क किये बिना हत्याएं कर रहे हैं। अब यह लड़ाई न तो सिखों द्वारा बदले की भावना से की जा रही है और न ही इसका उद्देश्य सिखों के सम्मान की रक्षा करना है, अन्यथा सिखों को ही बड़ी संख्या में उसी क्रूरता से निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जिस क्रूरता से आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बनाया करते थे?

१९८७ के दिसंबर में हुई ९० हत्याओं में ७७ सिख और १६ हिंदू मारे गये थे। जनवरी १९८० में मारे गये कुल १४५ लोगों में ९१ सिख और फरवरी में मारे गये १५६ लोगों में १०० सिख थे। मार्च में पट्टी में जिस १८ सदस्यीय परिवार की क्रूरतापूर्वक हत्या हुई थी, उसमें एक ८६ वर्ष के वृद्ध, छह माह की दुधमुंही बच्ची और एक गर्भवती महिला को भी उसी क्रूरता से मार दिया गया था।

महान गुरुओं के नाम पर उनके बंदों की हत्या क्यों?

छाया : राना जसपाल सिंह

इस घर में किसी हिंदू देवी-देवता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं था, बल्कि यह परिवार सिख गुरुओं का उपासक था और उस घर में सिख गुरुओं के ही चित्र लगे थे। पंजाब के देहाती इलाकों में इस समय इतना आतंक है कि रात में दरवाजे पर दस्तक सुनकर सिख परिवारों के भी कलेजे कांप जाते हैं।

आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के देहाती इलाकों से अब सिख भूस्वामी और सिख व्यापारी भी बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, जबकि पिछले दो वर्षों से हिंदू ही देहाती इलाकों से भाग रहे थे। जो हिंदू युवक वहां से भाग नहीं पाये, उन्होंने दाढ़ियां व सिर के बाल बढ़ा लिये और कड़ा पहनकर सिखों की तरह रहने लगे, लेकिन अब तो हालत यह है कि उन इलाकों के सिख युवक भी आतंक के साये में जी रहे हैं।

अमृतसर में शांति समिति के सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति सरदार दलबीर सिंह के युवापुत्र का कहना है, "इस सचाई को हमें साफ तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां रह रहे हम सभी लोग भाग्य के भरोसे हैं।" अमृतसर शहर में रहनेवाले सिख ऐसी ही आतंक की मानसिकता में जी रहे हैं, इसके बावजूद अमरीका और कनाडा के सिख यह मानकर आतंकवादियों को धन दे रहे हैं कि सिखों को भारत सरकार से खतरा है। विदेशों से आनेवाली इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल अब आतंकवादी दूरदराज के गांवों के सिख भूस्वामियों को धन वसूलने के लिए धमकी देने में कर रहे हैं। देहाती इलाकों के सिख परिवारों को आतंकवादियों को शरण देने और उनके हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है। इनकार करने पर आतंकवादी उनकी हत्या कर देते हैं और सिख परिवारों का यही वर्ग आतंकवादी हत्याओं का शिकार हो रहा है।

खालिस्तान कमांडो फोर्स व भिंडरांवाले टाइगर्स आर्मी के लैटर-हेड्स पर चेतावनी भरे पत्र लिखकर सिख भूस्वामियों से एक से डेढ़ लाख रुपए तक की मांग की जाती है और मांग पूरी न होने का मतलब 'सत्यानाश' होता है। तब उनके सामने इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाता कि या तो वे इलाका छोड़कर भाग जायें, या आतंकवादियों की गोलियों का सामना करें। अधिकांश भू-स्वामी इतना धन देने में असमर्थ रहते हैं और मारे जाते हैं, जबकि इसके पूर्व आतंकवादियों द्वारा हिंदू व्यापारियों को ही धमकी भरे पत्र भेजे जाते थे। यही वजह है कि पंजाब में आज सिख अधिकांश संख्या में मारे जा रहे हैं।

पिछले चार सालों में डीआईजी अटवाल सहित कुछ सिख सिपाहियों की हुई हत्याओं की बात तो समझ में आती थी कि आतंकवादी सुरक्षाबलों और पुलिस में स्थित अपने विरोधियों का सफाया कर रहे थे, लेकिन आज तो उन सिखों को भी आतंकवादियों द्वारा मारा जा रहा है जो उन्हें पनाह देने या धन देने से इनकार कर देते हैं। हाल ही कुछ सिख परिवारों का आतंकवादियों ने इसलिए भी सफाया कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी निजी दुश्मनी के कारण आतंकवादियों को ऐसा करने के लिए धन दिया था। एक परिवार की मौत हो जाने के बाद उसकी संपत्ति पर उस परिवार के निकटस्थ संबंधियों का स्वामित्व हो जाता है। ऐसा स्वामित्व पाने के लिए भी आतंकवादियों को धन देकर हत्याएं करवायी जा रही हैं। पहले भी धन-संपत्ति के लिए ऐसी हत्याएं पंजाब में पेशेवर हत्यारों द्वारा करवायी जाती रही हैं। १९७७ में जब पंजाब में आतंकवाद का नामोनिशान नहीं था, उस वक्त जमीन के झगड़ों या निजी दुश्मनी की वजह से अमृतसर और सीमावर्ती गांवों में ६०० सिखों की हत्याएं हुई थीं और आज ऐसे पेशेवर हत्यारों का काम आतंकवादी करने लगे हैं। पिछले एक साल में ऐसी किसी हत्या की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं हुई है कि किसी गैरआतंकवादी ने कोई हत्या की हो। हां, पुलिसवालों द्वारा व्यक्तिगत रंजिश से की गयी कुछ हत्याओं की प्रथम सूचना रिपोर्टें अवश्य दर्ज हुई हैं। अमृतसर जिला सदैव अपराध प्रभावित क्षेत्र रहा है और मांड के बीहड़ों में अपराधी शरण पाते रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे सिख अपराधी पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपनी दाढ़ियां कटवा देते थे और इसके पीछे उनका उद्देश्य कतई धार्मिक नहीं रहता था, जबकि आज आतंकवादी यह सब धर्म के नाम पर कर रहे हैं। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दिनों कुछ सिख जर-जोरू और जमीन के लिए भी मारे गये हैं, भले ही उन्हें मारनेवाले आतंकवादी रहे हों या पेशेवर अपराधी। दो मास पूर्व एक गांव में एक सदस्य को छोड़कर (जो कहीं बाहर गया हुआ था) पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया था, लेकिन उस घर के दो नौकरों को नहीं मारा गया। बाद में पता चला कि उस परिवार की हत्या संपत्ति के झगड़े के कारण हुई थी, इसी कारण नौकरों को नहीं मारा गया था। लेकिन अधिकांश सिख मुखबिर होने के संदेह में या सहयोग न करने पर आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं। अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक सिख प्रोफेसर ने कहा, "सहयोग न करनेवाले सिखों के प्रति वे भीषण प्रतिहिंसक कार्यवाही करते हैं।"

गत जनवरी में मारे गये ६१ सिखों में जीटी रोड पर खिलचरियन के समीप स्थित ढुलका बेनियन गांव के निरंजन सिंह की पुत्रवधु, एक पुत्री और दो पुत्र भी शामिल थे। उनके पुत्र झिलमन सिंह ने पुलिस की मदद की थी। झिलमन सिंह को गांव के बाहर सरेशाम मार डाला गया। आतंकवादियों ने इसके एक सप्ताह बाद अन्य सिख परिवारों को सबक सिखाने के लिए योजनापूर्वक निरंजन सिंह के घर पर धावा बोलकर उक्त हत्याएं कीं। निरंजन सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। उनका पुत्र सुरिंदर सिंह भागने में सफल हो गया, लेकिन उसके छोटे भाई परगट सिंह को आतंकवादियों ने मार डाला। परिवार के बचे लोगों ने राधा स्वामी संप्रदाय द्वारा संचालित साधू आश्रम में पनाह ले ली है, जहां उनके जैसे ८५० भुक्तभोगी शरण पाये हुए हैं। उनमें वे विधवाएं भी हैं, जिनके परिजन क्रूरतापूर्वक आतंकवादियों द्वारा मार डाले गये।

बहरहाल, समझा जाता है कि मार्च में पंथिक कमेटी ने कुछ हत्याओं में अपना हाथ होने से इनकार करते हुए सिखों की हत्या न करने के निर्देश जारी किये हैं। कारण स्पष्ट है। आतंकवादी खासतौर से उन ग्रामीण सिखों की सहानुभूति खो चुके हैं जो अभी तक यह समझते थे कि आतंकवादी सिख धर्म की रक्षा और गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। आतंकवादियों के प्रति आम सिखों में बढ़ती घृणा से सावधान होकर आतंकवादी गिरोहों के सूत्रधारों ने आतंकवादियों से सिखों को बख्श देने के निर्देश दिये हैं। इससे परोक्ष रूप से हत्याओं की संख्या कम हो सकती है। लेकिन क्या आतंकवादियों के सभी गुट इस निर्देश का पालन करेंगे? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए धन, और सुविधाओं का लोभ, धर्म रक्षा के उत्साह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का स्वयंभू जनरल लाभ सिंह पहले सिपाही सुखिदर सिंह था। लोग उसे सुक्खा सिपाही कहकर पुकारते थे। समझा जाता है कि वह ४५ ग्रामीण परिवारों के सफाये के लिए जिम्मेदर है, जिनमें ६० महिलाओं और २० बच्चों की भी क्रूरतापूर्वक हत्याएं हुई थीं। इनमें अधिकांश सिख परिवार थे और ये सभी पुलिस के मुखबिर नहीं हो सकते। मारा गया १५ महीने का शिशु लाखा सिंह पुलिस से क्या मुखबिरी करेगा। भ्रष्टाचार के कारण लाभ सिंह की पुलिस से छुट्टी हुई थी और अब तो वह भारत में है भी नहीं।

अतः इस बात की संभावना ही अधिक दिखायी देती है कि सिखों को न मारने के निर्देश का सभी आतंकवादी गुटों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जब तक सिख परिवार आतंकवादियों की धन, शराब और शबाब जैसी मांगों को पूरा करते रहेंगे, तभी तक वे अपने को सुरक्षित मान सकते हैं। होशियारपुर से १० किमी दूर साहरी गांव में होली के अवसर पर जो कुछ हुआ, उससे साफ जाहिर है कि आतंकवादी सिखों को भी नहीं छोड़ेंगे। वहां तीन सौ वर्ष पुराने महंत गुरलाल दास डेरा के परिसर में सिख और हिंदू संयुक्त रूप से गुरुनानक देव जयंती और होली उत्सव-मना रहे थे। डेरा-परिसर में एक ठाकुरद्वारा और एक शिव मंदिर भी है। उत्सव के समापन के दिन जैसे ही रासलीला समाप्त हुई, आतंकवादियों ने लोगों को घेर लिया और ३७ लोगों को गोलियों से भून दिया। मरनेवालों में आठ सिख भी थे। जब आतंकवादी हिंदुओं की हत्या करने के लिए हिंदुओं को छांट रहे थे, तो इन सिखों ने अपने हिंदू भाइयों से अलग होने से इनकार कर दिया था। आतंकवादियों ने इन सिखों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी हिंदुओं के साथ गोलियों से छलनी कर दिया। —दिल्ली ब्यूरो

पाकिस्तानी साठगांठ

हाल में बूटा सिंह ने जब लोकसभा को सूचित किया कि पंजाब में पाकिस्तान का उलझाव है, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। खबरें थीं कि दिसंबर, १९८७ में लाहौर के निकट डेरा बाबा नानक में एक बैठक हुई है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों तथा अमरीका और इंग्लैंड के सिखों ने भाग लिया है। इन खबरों की पुष्टि उन घातक हथियारों से हो जाती है जो इस समय पंजाब के आतंकवादियों के पास देखे जा रहे हैं। एके-४७ चीनी राइफलें, एआर-१५५ अमरीकी बंदूकें और आरपीजी राकेट जैसे हथियारों के सहसा दिखायी देने और जनवरी से हत्याओं में आयी बाढ़ से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को नया गुरमंत्र दिया है। कानपुर में हुई इंका विधायक विलायती राम कत्याल की हत्या के बाद मिले हथियारों के जखीरे और पकड़े गये हत्यारों से मिली जानकारी से भी यह साबित होता है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर हथियार मुहैया करवा रहा है, बल्कि उनको पंजाब से बाहर हिंसा और तोड़फोड़ करने की शिक्षा भी दे रहा है।

सीमा पार से आये राकेट

छाया: [illegible] जसपाल सिंह

दिसंबर की बैठक शायद पाकिस्तान के लिए इसलिए जरूरी हो गयी थी, क्योंकि उस समय आतंकवादियों पर सुरक्षाकर्मियों का भारी दबाव होने के कारण उनको मांड जैसे ठिकानों पर भी छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। हताश होते आतंकवादियों की फिर से हौसलाअफजाई करने और उन्हें नयी रणनीति बताने के लिए पाकिस्तान ने यह बैठक करना आवश्यक समझा था। खालिस्तान के एक नवोदित झंडाबरदार अमरीकी सिख औलख ने इस बैठक में भारी मात्रा में एआर-१५५ बंदूकें उपलब्ध कराने के वादे के साथ कहा था कि 'पैसे की कोई चिंता नहीं'। नौकरी से निकाला गया सुक्खा सिपाही जो अपने आपको ले० जनरल लाभ सिंह कहता है, इस समय पाकिस्तान में है और वहां से आतंकवादियों की गतिविधियों में तालमेल बिठाने तथा नयी रणनीति बनाने के काम में लगा है।

पकड़े गये आतंकवादियों से स्पष्ट जानकारी मिली है कि 'पाकिस्तान ज्योग्राफिकल सोसाइटी' के नाम से सीमा के निकट कार्यरत एक एजेंसी के माध्यम से आतंकवादियों की भरती होती है। इनको पाकिस्तान स्थित विभिन्न शिविरों में हत्या व तोड़-फोड़ का प्रशिक्षण देकर वापस भेजा जाता है। पाकिस्तान में कुछ मुख्य प्रशिक्षण शिविर डक्का, संधू, नरोवल और रंगपुरा में हैं। प्रशिक्षकों में कर्नल मुनीर, कर्नल राजा और कर्नल चौधरी का नाम भी शामिल है। ये नाम नकली हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सुनियोजित ढंग से आतंकवादियों को तैयार करने में लगा है। और-तो-और इस समय सर्वाधिक सम्मानित जसबीर सिंह रोडे भी एक समय पाकिस्तानी सूचना मंत्री के साथ इस्लामाबाद और लाहौर

बेअसर : पाक सीमा पर चौकसी

में ठहरा करते थे। उस समय रोड़े भारत के खिलाफ नफरत उगला करते थे और खालिस्तान का प्रचार किया करते हैं।

पिछले साल तक पाकिस्तान शस्त्रों की सप्लाई तो जारी रखे था, लेकिन उसकी यह कोशिश थी कि उसका भेद न खुले। भारत ने जब-जब विरोध किया, पाकिस्तान ने अपनी संलग्नता से इनकार करने में कोई कोताही नहीं की, लेकिन जब वहां से लौटे आतंकवादियों के नामों और प्रशिक्षण शिविरों के स्थानों का ब्यौरा दिया गया, तो उसके पास इनकार करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखायी दिये। हां, उसनें जवाब़ी आरोप जरूर लगाये कि भारत सिंध में बगावत भड़का रहा है। इस्लामाबाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो इशारे में यह बात भी जतायी थी की यदि भारत सिंध में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, तो पाकिस्तान भी पंजाब से अपने हाथ खींच लेगा। आश्चर्य की बात है कि एक साल तक भारत ने जोरदार ढंग से पाकिस्तान से नहीं कहा कि वह पंजाब में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। शायद उसका कारण यह था कि आतंकवादियों पर सुरक्षाकर्मी भारी पड़ रह थे। लेकिन इस वर्ष जनवरी में जब से हिंसा की नयी बाढ़ आयी है, भारत ने खुलकर पाकिस्तान को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों।

चाहे प्रमाणित करना आसान न हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्टिंगर मिसाइलें और राकेट जैसे हथियार बिना पाकिस्तान की ज़ानकारी और शह के पंजाब में नहीं आ सकते। २००० के करीब एके-४७ राइफलें, ५०० राकेट तथा भारी मात्रा में गोली-बारूद क्या बिना पाकिस्तान की जानकारी के भारत की सीमा में ठूंसा जा सकता है? यह ब़ात दूसरी है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या कम संख्या होने के कारण भारतीय सुरक्षाकर्मी इसको न रोक पाये।

इस समय पाकिस्तान में मुजाहिदीनों के पास असंख्य हथियार हैं और वे इनको बेचते हैं। एक अत्याधुनिक रायफल जिसकी कीमत ४५००० है, वह थोक में खरीदने पर ८००० से १०,००० रुपए में वहां उपलब्ध है। जाहिर है ये राइफलें, राकेट और अन्य परिष्कृत हथियार इन्हीं मुजाहिदीनों से पंजाब पहुच रहे हैं। लाभ सिंह जैसे लोगों के पास विदेशों से अंधाधुंध पैसे पहुंच ही रहे हैं। इन पैसों से हथियार खरीद कर ८०० किमी में फैली सीमा को विभिन्न जगहों पर पार करके भारत में पहुंचाये जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि पिछले दो सालों में सीमा के पास पाकिस्तान की ओर मजारों और भारत की ओर गुरुद्वारों की बाढ आयी हुई है। ये धार्मिक स्थान इन हथियारों की आपूर्ति में काफी भूमिका निभा रहे हैं।

हालांकि, पाकिस्तान निरंतर कह रहा है कि पंजाब में वह खुरापात नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय गृहमंत्रालय का दावा है कि उसके पास पाकिस्तान स्थित प्रशिक्षण शिविरों के वीडियो टेप हैं। इन टेपों को पाकिस्तानी अधिकारियों को दिखाये जाने की भी बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये अधिकारी इन सबूतो का तुरंत खंडन नहीं कर पाये थे। लेकिन बाद में इस्लामाबाद के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया था। भारत चाहे, तो इन टेपों को स्वदेशी और विदेशी पत्रकारों को दिखाकर पोल खोल सकता है।

जहां तक सीमा को सील करने का सवाल है, वह सतलज नदी के लंबे-चौड़े पाट, दलदल और भारी झार-झंखाड़ को देखते हुए आसान नहीं है। लेकिन नाजुक स्थानों पर कांटेदार तार लगाकर और चौकसी बढ़ाकर यह कार्य हो सकता है। क्योंकि वास्तविक खतरा तब उत्पन्न होनेवाला है, जब जिनेवा समझौते के तहत रूसी सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली जायेंगी। पाकिस्तान की तीन डिवीजन सेना का अफगानी सीमा पर कोई काम नहीं रह जायेगा और मुजाहिदीनों को हथियारों की जरूरत नहीं होगी। ऐसी हालत में पाकिस्तान से बातें करना या हथियारों को पंजाब में घुसने से रोकने के लिए मुकम्मल क़दम उठानें होंगे। यदि भारत पंजाब से आजिज आ चुका है, तो पाकिस्तान भी सिंध की घटनाओं से भयभीत है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से समस्या का बातचीत से हल निकलने की संभावना है। फिर पाकिस्तान की आम जनता कुछ आतंकवादियों के लिए युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में यदि आतंकवादियों को हथियार मिलने बंद हो गये, तो फिर उनसे सुरक्षाकर्मी आसानी से निपट लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश का बदला लेने के लिए आतुर पाकिस्तान क्या आतंकवादियों को सहायता प्रशिक्षण देने से बाज आयेगा?

—दिल्ली ब्यूरो

आतंकवादी : तब और अब

आज के आतंकवादियों के खालिस्तान अंकित हथियार

चाचा जरनौल सिंह भिंडरांवाले के नंगी तलवारें व ३०३ की राइफलें लिये खुली दाढ़ी लहराते व केसरिया पगड़ी बाधे अनुयायियों की जगह आज भतीजे जसबीर सिंह रोड़े के दाढी-मूंछ विहीन अत्याधुनिक एके-४७ और एके-१५५ हथियारों से लैस शाल लपेटे खूनी आंखोंवाले आतंकवादियों ने ले ली है। अंतर वेशभूषा और हथियारों में ही नहीं आया है, बल्कि तबके आतंकवादी जहां हत्याओं और अलगाववादी गतिविधियों को धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश करते थे और कम-से-कम धर्म से खौफ खाते थे। वहीं आज के आतंकवादियों को धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। वे पाकिस्तान से प्राप्त एके-४७ राइफल की नली छाती से टिकाकर छह माह तक के सोते हुए शिशुओं को गोलियां मार देते हैं।

क्या आतंकवादी, सिखों के आहत

सम्मान का बदला लेने के लिए ऐसे पाप-कर्म कर रहे हैं, क्या हिंदू-सिखों की हत्याएं भी इसी मकसद से की जा रही है? दो पुत्रों की अपने सामने नृशंस हत्या देखनेवाला एक वृद्ध बड़े दुख से पूछता है, "हर रात पंजाब में जो खून बहता है क्या उससे स्वर्ण मंदिर शुद्ध किया जा सकता है?" वह वृद्ध अपने दुख में यह भूल गया है कि ऐसे सवालों का जवाब पंजाब में आज गोलियों से दिया जा रहा है।

वास्तविकता यह है कि बब्बर खालसा को छोड़कर प्रायः सभी आतंकवादी संगठन अपने पूर्व चरित्र से गिरकर आज पेशेवर हत्यारे बन चुके हैं। इनमें से अधिकांश संगठन पाकिस्तान व अन्य विदेशी ताकतों द्वारा धन और हथियारों से पोषित होते हैं। आधा दर्जन स्टेनगनधारी कमांडो द्वारा रक्षित बेरिकेटेड मकान में रहनेवाले सतपाल डांग पूछते हैं, "जो विदेशों से निर्देशित होते हैं, जो पेशेवर हत्यारे बन चुके हैं और जिनकी तस्करों से साठगांठ है, वे पंथ की रक्षा कैसे कर सकते हैं?"

चाचा की जगह अब भतीजा : रोडे के चाचा भिंड़रांवाले, जिनके कारण ब्ल्यू स्टार की नौबत आयी थी छाया : करम सिंह

भिंडरांवाले के जमाने के मुकाबले आज हालात बहुत बदल गये हैं। उस समय भी हत्याएं होती थीं, लेकिन तब उन्हीं कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता था जो भिंडरांवाले की मांगों और निर्देशों को मानने से इनकार करते थे। भिंडरांवाले ने अपने अनुयायियों को 'ब्रेनवाश' कर यह विश्वास दिला दिया था कि दिल्ली सरकार सिखों के साथ पक्षपात कर रही है। इसके प्रमाण स्वरूप कहा जाता था कि दिल्ली सरकार ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। उस समय मुक्तसर बस हत्याकांड पहली ऐसी आतंकवादी कार्यवाही थी, जिसमें सामूहिक रूप से एक वर्ग विशेष के लोगों की हत्या की गयी थी। इस हत्याकांड में १४ लोग मारे गये थे। और इसका उद्देश्य सरकार को भिंडरांवाले की ताकत का अहसास कराना था। उस वक्त भी सिर्फ हत्याएं हुई थीं। किसी बस यात्री को न तो लूटा गया था और न ही कोई बलात्कार हुआ था। आपरेशन ब्ल्यू स्टार और १९८४ के दिल्ली-दंगों के बाद आतंकवादी पंथ के रक्षक और दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंड देनेवाले की भूमिका निभाने लगे थे। वे उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर को उनके नजरिए से अपवित्र किया था या जिन्होंने दिल्ली में सिखों को मारा था। तब भिंडरांवाले तो नहीं थे, लेकिन उनके भाषणों के कैसेट हजारों की तादाद में वितरित किये गये थे। आतंकवादियों में पंथ की रक्षा के निमित्त साहस का संचार करने के लिए भिंडरांवाले के भाषणों के कैसेट सुनाये जाते थे। तब तक ये आतंकवादी पेशेवर नहीं हुए थे, लेकिन भिड़रांवाले की अनुपस्थिति में दिशाहीन जरूर हो गये थे। उस समय महिलाओं को शायद ही आहत किया जाता था और बच्चे तो पूरी तरह सुरक्षित थे।

लेकिन आज आतंकवादियों में ऐसा कोई आग्रह नहीं रह गया है, वे बैंकों को लूट रहे हैं और हिंदू-सिख दोनों से जबरिया धन वसूल कर रहे हैं।

वे सिख परिवारों को शरण और भोजन देने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाल ही पट्टी के निकट तीन आतंकवादी एक सिख घर में चार दिनों तक जबरन टिके रहे। रात में वे वारदात करने चले जाते थे और सुबह होते ही वापस आ जाते थे। उन्होंने इस सिख परिवार को खाना एवं अन्य सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक वे वहां रहे, उन्होंने प्रतिदिन उस परिवार की दो युवा लड़कियों के साथ बलात्कार किया।

पंजाब के चार जिलों—अमृतसर, फरीदकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में तो हालात और भी खराब हैं। वहां एक लंबे अर्से से इन आतंकवादियों का दबदबा व आतंक कायम है। इस निरंकुश स्थिति से आतंकवादी धर्मभ्रष्ट हो गये हैं। उनमें धार्मिक जोश व अनुशासन समाप्त हो गया है और वे लूटपाट, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि हर तरह के अपराधों में लिप्त है।

इन आतंकवादी गिरोहों द्वारा की गयी हत्याओं का आलम यह है कि वर्ष १९८८ के प्रथम ९० दिनों में ७२० हत्याएं हुई है—यानी प्रतिदिन औसतन ८ हत्याएं। अकेले मार्च महीने में २९९ लोगों ने जान से हाथ धोये थे। बरनाला के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में लगभग ४०० लोग मारे गये थे, लेकिन सिद्धार्थशंकर रे ने जब से (११ मई, १९८७) शासन संभाला है तब से साढ़े दस महीने (३१ मार्च, १९८८) में १५९२ लोग मारे जा चुके हैं।

भिंडरांवाले के जमाने के आतंकवादी अपने हथियारों का प्रदर्शन करने और खालिस्तान की बात करने में थोड़ा खौफ खाते थे, लेकिन आज के आतंकवादियों में अब वैसा कोई खौफ नहीं है। स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा में खंबों के सहारे खड़े शाल लपेटे युवा आतंकवादी हथियारों के साथ देखे जा सकते हैं। वे मंदिर के अंदर निगरानी करते हैं तो २० आतंकवादी गुरुनानक सराय (मंजी साहिब) की छत पर खड़े होकर स्वर्ण मंदिर के समूचे क्षेत्र पर बारीक नजर रखते हैं। स्वर्ण मंदिर में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बहुत कम हो गयी है। जो तीर्थयात्री वहां जाते भी हैं, उन्हें भयपूर्वक इन आतंकवादियों को देखते हुए देखा जा सकता है। अब तो स्वर्ण मंदिर में मुख्यतः वे ही लोग जाते ~~हैं, जो~~ वहां से संबंधित हैं या जो स्वर्ण मंदिर में डेरा डाले आतंकवादियों के इलाके के हैं।

आज आतंकवादी खुद को ही कानून और प्रशासन मानने लगे हैं। छपे हुए लेटर हेड्स पर वे लोगों को धन भेजने, दुकान बंद करने या सामग्री भेजने के लिए हुकुम जारी करते हैं। वे आरामतलब हो गये हैं—ऐयाशी के शराब-शबाब सहित सारे ठाठ उनके पास हैं और हुकुमबजाने वाले लोगों की भी उनके पास कमी नहीं है। दो युवा आतंकवादियों ने हाल ही खालिस्तान के नक्शे वितरित किये हैं और वे लोगों को बताते भी हैं कि किस तरह थोड़े समय में ही वे 'खालिस्तान' का निर्माण कर डालेंगे। भिंडरांवाले के अनुयायी अनिवार्य रूप से पूजा-पाठ व अरदास किया करते थे, लेकिन आज आतंकवादियों को इसके लिए शायद ही वक्त मिलता हो। —दिल्ली ब्यूरो

निरर्थक कवायद

लुंज-पुंज प्रशासन, हताश जनता

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लगभग एक वर्ष बाद स्थिति यह है कि गृह मंत्री बूटा सिंह आतंकवाद को सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा देने को बाध्य हो गये हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान की विफलता का ज्वलंत उदाहरण यही है कि आज न केवल आतंकवादियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वरन उनकी कार्यशैली और उनके हथियार भी आधुनिकतम हो गये हैं। पुरानी बंदूकों का स्थान यदि एके-४७ के साथ स्टिंगर-मिसाइलों और मोर्टरों ने ले लिया है, तो गिने-चुने दिग्भ्रमित दिशाहीन सांप्रदायिक कट्टरपंथियों का स्थान सुशिक्षित-प्रशिक्षित और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नौजवान विद्रोहियों के हाथ में पहुंच गया है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति में आये इस गंभीर परिवर्तन का कारण क्या है?

यह सब सहसा नहीं घटित हुआ। इसे एक योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत सरंजाम दिया गया है। 'माया' से बातचीत में एक जानकार सूत्र ने बताया कि लगभग ६ माह पूर्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि आतंकवादी बड़ी तादाद में अत्याधुनिक हथियार सीमा पार से लाकर एकत्र कर रहे हैं और वे किसी बड़ी मुह्म्मि की फिराक में हैं। स्वर्ण मंदिर में इन हथियारों का भंडारण जिस कमरे में किया गया था, उसके नंबर तक की जानकारी दे दी गयी थी। किंतु इसकी रोकथाम की कोई कोशिश न तो केन्द्र और न ही राज्य की ओर से हुई। आंखें तब खुलीं, जब हाल में आतंकवादियों ने राकेट छोड़े। पंजाब के गली-मोहल्लों में यह चर्चा है कि पहला राकेट ५-६ माह पूर्व सीआरपीएफ की एक जीप पर छोड़ा गया था। सौभाग्य से जीप तो बच गयी, किंतु उस स्थान पर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गफलत के अनेक कारण बताये जाते हैं।

भ्रष्टाचार: चंडीगढ़ स्थित एक जाने-माने राजनीतिक पर्यवेक्षक ने नाम न लेने के अनुरोध सहित बताया, "राज्य की आज सबसे बड़ी समस्या आंतकवाद नहीं, भ्रष्टाचार है। इसी कारण आतंकवादी फल-फूल रहे हैं। सीमा पार से होने वाली हथियारों, मादक द्रव्यों और सोने की तस्करी घूस के बलबूते पर ऐलानिया जारी है। वहां तैनात सीआरपीएफ तथा अन्य सुरक्षाकर्मी मुट्ठी गर्म होते ही सूरदास बन जाते हैं। फर्क यही है कि कभी काम ५०० में हो जाता है और कभी ५ हजार रुपये में।"

सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति से भलीभांति परिचित एक राजनीतिक कार्यकर्ता की टिप्पणी थी कि निश्चित कीमत अदा करने के बाद यदि कोई दिन में पांच बार सीमा पार करना चाहे, तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होती। इसलिए राकेट जैसे संघातक हथियारों का पंजाब में आ जाना आश्चर्यजनक नहीं है।

उपर्युक्त कथन पूरा नहीं आधा सच है। पुलिस अकर्मण्यता और अक्षमता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी अपनी विवशताएं हैं। एक हेडकांस्टेबल ने 'माया' को बताया, "हमारे बारे में अकर्मण्यता के आरोप पूरी तरह सही नहीं है, भ्रष्टाचार के जरिये कुछ हथियारों के आ जाने से इनकार नहीं, किंतु हमारा सीमा क्षेत्र जितना विस्तृत और दुरूह है, उसकी पूरी तरह चौकसी असंभव है। सीमा विस्तार और स्थिति की तुलना में सुरक्षाकर्मियों की संख्या अत्यधिक नगण्य है।"

विभाजित नौकरशाही: जहां तक प्रशासनिक कमजोरियों का सवाल है, उसमें एक ओर जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहीं नौकरशाही पूर्णतया विभाजित है। इनमें से खालिस्तान-समर्थक भले ही न हों, किंतु मुंडों (नौजवानों) के प्रति सहानुभूति रखने वालों की कमी नहीं है। मध्य और छोटे वर्ग के अधिकारियों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक मानी जाती है। यद्यपि पुलिस अधीक्षक केपीएस गिल इसका खंडन करते हैं, किंतु भाजपा सचिव कृष्णलाल शर्मा का दावा है, "प्रशासन, विशेषकर पुलिस में मध्यम और निम्न स्तर पर खालिस्तान-समर्थकों की काफी घुसपैठ है।"

इसका फल यह है कि एक तो आतंकवाद-विरोधी मुहिम के संबंध में यदि कोई नीति बनती भी है, तो उसको कारगर ढंग से लागू नहीं किया जाता। इससे भी गंभीर पहलू यह है कि अकसर नीति के लागू होने के पूर्व ही उसकी खबर आतंकवादियों तक पहुंच जाती है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलअंदाजी को कारण बनाकर राष्ट्रपति शासन लागू कराकर बड़े जोरशोर से और उम्मीदों के साथ जिस सिद्धार्थ शंकर रे ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी, वह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

करना तो दूर, उसकी चर्चा अथवा उस पर एक कदम उठायें भी नहीं गये। कुछ समय पूर्व चंडीगढ़ की एक प्रेस कांफ्रेंस में जब अनेक संवाददाताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक निष्क्रियता और तटस्थता का जोरदार शब्दों में जिक्र किया, तो राज्यपाल रे पहले तो बगलें झांकते नजर आये, फिर सवालों की निरंतर बौछारों ने उन्हें यह कहने को विवश कर दिया कि विभिन्न समस्याओं में उलझे रहने के कारण वह इस मामले में कदम उठाने में विवश रहे हैं। उन्होंने शीघ्र कोई कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन उन पत्रकारों को ही नहीं, राज्य की जनता को भी आज तक उस कार्रवाई का इंतजार है।

रे क्या करें? : रे की अपनी विवशताएं कुछ कम नहीं हैं। उनकी अब तक की विफलता का प्रमुख कारण यह है कि रे नये हैं और प्रशासन पुराना। प्रशासनिक कमजोरियों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनमें मूलगामी सुधार लाना सहज नहीं है। फिर रे के हाथ में कोई अलादीन का चिराग भी नहीं है। किंतु उन पर यह आरोप लगाने वालों की राज्य में कमी नहीं है कि वह केन्द्र सरकार की मात्र एक कठपुतली हैं। उनके आज तक उठाये हर कदम केन्द्र से प्रेरित-संचालित हैं।

जहां तक केन्द्र द्वारा उनको दिशा-निर्देश और आदेश देने का प्रश्न है, स्वयं केन्द्र दुविधाग्रस्त है। उसकी कोई निश्चित नीति नहीं है। आज एक कदम उठाया जाता है, तो कल दूसरा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के हाथ मजबूत करने की जगह, उन्हें प्रायः पीठ पीछे बांध दिया जाता है। वैसे जिन इलाकों में आतंकवादी हत्याएं होती हैं, वहां शोकग्रस्त परिवार को ढ़ाढ़स बंधाने रे अकसर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा राजभवन में बैठकर प्रशासन करने की जगह सदैव जनता के बीच ज़ाना रे की अपनी खासियत है।

रे के खिलाफ आरोपों के बारे में उनके निकटस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल स्वंय इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। यद्यपि 'माया' से गत दिनों अपने साक्षात्कार में रे नें इस बात का खंडन किया था। किंतु पंजाब के सत्ता-गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि केन्द्रीय गृह मंत्री बूटा सिह और राज्यपाल रे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते।

बहरहाल, ऐसा लगता है कि रे ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। राजनीति के कुशल खिलाड़ी होने के नाते, न तो वह राज्य में प्रशासनिक अक्षमता के विरुद्ध कड़े कदम उठाकर अपने को अप्रिय बना सकते हैं और न केन्द्र की अवज्ञा कर मनमाना कदम उठा सकते हैं। विशेषकर ऐसे राजनीतिज्ञ के लिए जो लगभग दस साल तक गुमनामी के

साक्षात्कार/**दर्शन सिंह रागी**

'सरकार ने मेरी स्थिति हास्यास्पद बना दी है'

गुरुवाणी के प्रख्यात गायक दर्शन सिंह रागी जब अकाल तख्त का मुख्य जत्थेदार बने थे, तब यह उम्मीद की गयी थी कि वह पंजाब समस्या का हल निकालने में मददगार होंगे। वह इस दिशा में प्रयत्नशील भी हुए, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने शांति-सुलह की बातें करनी शुरू कीं, वैसे ही आतंकवादियों से प्रभावित धड़े ने उन्हें पद से हटा दिया। पंजाब में फिर से उफने आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में 'माया' ने उनसे पंजाब मसले पर विस्तार से बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, उनसे हुई बातचीत के अंश:

माया: आपके विचार से सरकार को किससे बातचीत करनी चाहिये?

रागी: पहली बात तो यह है कि जो बातचीत और फैसले होते भी हैं, उससे सरकार मुकर जाती है अथवा लागू नहीं करती। मसलन, संत लोंगोवाल ने सरकार से जो समझौता किया, उसे राज्य की जनता ने भी अपना समर्थन प्रदान किया था। किंतु सरकार ने समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया। यही रवैया बरनाला के साथ सरकार ने किया। संत लोंगोवाल की शहादत और बरनाला की सरकार दोनों एक प्रकार से निष्फल रहीं।

माया: आपके मुख्यग्रंथी पद से हटने के सिलसिले में कहा जाता है कि उग्रपंथियों ने आपको भयभीत करके भगा दिया।

रागी: यह बिलकुल गलत है। जब तक बातचीत जारी रही, तब तक वे लोग हमारे साथ रहे। जब सरकार स्वयं बातचीत के बाद पीछे हट गयी, तभी उन लोगों ने मुझसे कहा कि केन्द्र सरकार केवल हत्याएं कराने के लिए वक्त गुजार रही है और टाल मटोल का रुख अपना रही है। फिर भी उन लोगों ने मुझे दुबारा बातचीत करने का मौका दिया। मगर सरकार फिर पीछे हट गयी।

माया: सरकार क्यों पीछे हट गयी?

रागी: यह तो आप सरकार से या सुशील मुनि से पूछ सकते हैं। ऐसी हालत में मेरे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था कि मैं सरकार से हमेशा के लिए समझौता वार्ता बंद कर दूं। किंतु मैंने समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमें बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना होगा। बहरहाल, सरकार ने अपने ही लोगों के सामने मेरी स्थिति हास्यास्पद बना दी है।

माया: इधर सिख अधिक संख्या में मारे जा रहे हैं। इसका क्या कारण है?

रागी: यही मेरा भी सवाल है। लगभग ६० प्रतिशत मरनेवाले सिख ही हैं। क्या सिखों की हत्या करके ही सिख खालिस्तान बना पायेंगे? इसका मतलब है खालिस्तानी लोग नहीं मार रहे हैं। मारनेवाले दूसरे हैं, जो सिखों को बदनाम करना चाहते हैं। इसके पीछे साजिश राजनीतिक"है।

माया: गत होली के दौरान सिखों ने मौत के चंगुल में फंसे अपने हिंदू भाइयों के साथ-साथ मर जाना पसंद किया, साथ छोड़ना नहीं।

रागी: यह इसकी ज्वलंत मिसाल है कि पंजाब में संप्रदायवाद नहीं है। उनमें आपस में प्यार है। पर ऐसे माहौल को सांप्रदायिक बना देने और फूट के बीज बो देनेवालों की भी कमी नहीं है।

माया: कहा जाता है कि जब भी अकाली सरकार बनी, तो आपसी झगड़ों से ज्यादा दिनों टिक नहीं पायी।

रागी: केन्द्र सरकार के पास बेपनाह ताकत है। वह विपक्ष की सरकार को चलने ही नहीं देती। कश्मीर की मिसाल लें। पहले साले-बहनोई (फारूख-गुलशाह) को अलग-अलग किया। सरकारें गिरायीं-बनायीं। फिर वहां तब तक सांप्रदायिक, क्षेत्रीय झगड़े आदि होते रहे और वे लोग देश के गद्दार भी कहलाते रहे, जब तक कि कांग्रेस को सत्ता में उनके साथ हिस्सेदारी नहीं मिल गयी।

—विजय दत्त

अंधेरे में रहने के बाद राजनीति की मुख्य धारा में आया हो, स्वेच्छा से ठोस पहल करना आसान नहीं होता।

रे ने समझौता भले ही कर लिया हो, किंतु पुलिस के छोटे-बड़े अधिकारी अत्यंत क्षुब्ध हैं। सरकार की दुरंगी नीति को समझ पाने में विफल इन सुरक्षाकर्मियों का मनोबल क्षीण हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 'माया' से कहा, ''जिन सरगना लोगों पर अनगिनत हत्याओं का आरोप हो और जिनकी गिरफ्तारी के लिए लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा हो, उन्हें दरबार साहब में ऐलानिया सरोपा देकर सम्मनित किया जाये, क्या इससे हमारा मनोबल नहीं टूटेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि कल उन्हीं के हाथों में बागडोर नहीं सौंप दी जायेगी? वैसी हालत में क्या वह हम से चुन-चुन कर बदला नहीं लेंगे?''

पुलिस की हताशा: यदाकदा प्रतिरोध का स्वर भी उभरता रहा है। जिस रोड़े को अत्यधिक खतरनाक करार देकर गिरफ्तारी के लिए रात-दिन एक किया गया था, उसी को आज अकाल तख्त का जत्थेदार बना दिया गया है। इसी तरह जिन ग्रंथियों को दरबार साहिब में 'खालिस्तान' का नारा लगाने के कारण गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर सम्मानित कर दिया गया।

इससे पुलिस का मनोबल जहां गिरा है, वहीं आतंकवादी वारदात में सहसा वृद्धि हुई है। पुलिस के इसी असंतोष को व्यक्त करते हुए कदाचित पुलिस महानिदेशक जूलियस रिबेरो कुछ समय के लिए कहीं दिखायी नहीं दे रहे थे और ऐसा लगता था कि समस्त कामकाज से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। यद्यपि सरकार का कहना है कि रिबेरो अपने एक आपरेशन के कारण कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले गये थे। किंतु आम जनता ~~के बीच~~ उनकी गैरहाजिरी पर आज भी प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। यही नहीं, केन्द्रीय गृह मंत्री व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री बूटा सिंह और चिदबरम की हाल की पंजाब-यात्रा के दौरान हुई बैठकों में अमृतसर के जाने-माने एसएसपी इजहार आलम की लगातार गैरमौजूदगी को भी लोगों ने इसी नजर से लिया है।

केन्द्र के इन दो प्रतिनिधियों ने राज्य के अधिकारियों से जो लंबी बातचीत की, उसे यद्यपि कुछ लोग आंखों में धूल झोंकना बता रहे हैं, किंतु एक अधिकारी का, जो बातचीत में मौजूद था, दावा है कि इससे नौकरशाही की जड़ता समाप्त होगी और कुछ दूरगामी अहम और फौरी फैसले लिये गये हैं। वैसे सरकार की अस्थिर और समय-कुसमय बदलने वाली नीति का सीधा प्रभाव सुरक्षा बलों पर विशेष रूप से पड़ा है। उनकी इतने अधिक दिनों की गैरहाजिरी ने आम जनता और आतंकवादियों के मन से उनके प्रति आदर व भय का भाव नहीं रह गया है। चंडीगढ़ की एक शिक्षिका ने बताया, ''आज 'थ्री-नाट-थ्री बंदूकों (सुरक्षाकर्मियों का आम हथियार) की कोई परवाह नहीं करता। स्टेनगन अवश्य भय पैदा करती है, किंतु बदकिस्मती से ये आतंकवादियों के पास अधिक हैं। हमारे सुरक्षाकर्मियों के पास कम।''

जहां तक भय का प्रश्न है, वह तो आतंकवादियों ने ग्रामीणों और आम जनता में पैदा कर ही रखा है। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यद्यपि पुलिस अधीक्षक केपीएस गिल ने अपने जवानों के अनेक बहादुरीपूर्ण कारनामों का 'माया' से उल्लेख किया, लेकिन वह दूर-दराज बसे गांवों में एक-दो की संख्या में तैनात पुलिसजनों की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। अनेक सुदूर गांवों का दौरा करके लौटे एक संवाददाता के अनुसार, ''यदि ग्रामीण अपने घर का दरवाजा शाम छह बजे बंद कर लेते हैं, तो वहां तैनात सुरक्षाकर्मी पौने छह बजे से ही अपने कमरे में अंदर से ताला लगाकर बैठ जाते हैं।'' कदाचित इसके लिए उन्हें सरासर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आतंकवादियों के सहसा वहां प्रकट हो जाने पर वह तादाद, हथियार और मनोबल तीनों दृष्टि से उनसे उन्नीस ही बैठेंगे। इसके अलावा परिवार की चिंता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर अलग से है। यही कारण है कि राज्य में बढ़ती हुई आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को हाल में तैनात किया गया है और सेना को भी मुस्तैद किया जा रहा है।

पंजाब की किस्मत का फैसला आज केंद्र के हाथ में है और केंद्र में समस्या से सीधी जुड़ी हस्तियां या तो अराजनीतिक प्रकृति की हैं या जिनके सीधे-सादे अपने निजी स्वार्थ हैं। विडंबना यह है कि पंजाब शतरंज का ऐसा खेल बन गया है, जिसकी पहली चाल पाकिस्तान के हाथ में है। उसके बाद ही भारत को जवाबी कार्रवाई के रूप में चाल चलनी पड़ती है। समस्या का समाधान इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पाकिस्तान किस हद तक जायेगा और क्या वह भारत को सीधी मुठभेड़ के लिए विवश कर देगा?

पंजाब की किस्मत का फैसला आज केन्द्र के हाथ में है और केंद्र में समस्या से सीधी जुड़ी हस्तियां या तो अराजनीतिक प्रकृति की हैं या जिनके सीधे-सादे अपने निजी स्वार्थ हैं। विडंबना यह है कि पंजाब शतरंज का ऐसा खेल बन गया है, जिसकी पहली चाल पाकिस्तान के हाथ में है। उसके बाद ही भारत को जवाबी कार्रवाई के रूप में चाल चलनी पड़ती है। समस्या का समाधान इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पाकिस्तान किस हद तक जायेगा और क्या वह भारत को सीधी मुठभेड़ के लिए विवश कर देगा? इसी संगीन मसले को शायद मद्देनजर रखते हुए सरकार को पंजाब में जरूरत पडने पर आपातकाल की व्यवस्था करने के लिए विवश होना पड़ा है। सरकार ने तीन सूत्री कार्यक्रम का भी ऐलान किया है—जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर सख्त चौकसी, सुरक्षाकर्मियों को अत्याधुनिक हथियार देना और आतंकवाद के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर अभियान चलाना। सरकार ने कट्टरपंथियों से बात चलाने और बात विफल होने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आपातस्थिति लागू करने का मन बना लिया है।

सरकार चाहे जो कदम उठाये, लेकिन अधिकांश लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। यही स्थिति पंजाब में उसकी कृपादृष्टि से उभरे सुरजीत सिंह बरनाला की हुई और आज जसबीर सिंह रोड़े की है। नतीजतन यदि व्यापक सिख समुदाय और आतंकवादियों, दोनों में अपना दबदबा और विश्वास स्थापित करने के लिए रोड़े सरकार के भावी कदमों में रोड़े अटकायें, तो कोई आश्चर्य न होगा। उल्लेखनीय है कि अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार के रूप में हाल में पदारूढ़ होने के बाद उन्होंने 'खालिस्तान' का नारा तो नहीं बुलंद किया, किंतु अपनी उस 'पूरन आजादी' की मांग करने का कोई मौका नहीं खोया है, जिसका अभी तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसी प्रकार यद्यपि उन्होंने सिख परिवारों की हत्या की निंदा की है, लेकिन आज तक कभी भी आतंकवादी हिंसा की भर्त्सना नहीं की है। हां, बैसाखी के दिन उन्होंने परस्पर विरोधी सिख संगठनों को एक करने की प्रक्रिया शुरू की है। यदि यह होता है, तो कम-से-कम यह बात तो सामने आयेगी कि सरकार को किससे बात करनी है। लेकिन यह भी साफ दिखायी देने लगा है कि नेतृत्व नौजवान अतिवादियों के हाथ में जा रहा है जो 'खालिस्तान' से कम कोई बात करने पर राजी ही नहीं दिखायी देते। ऐसी स्थिति में फिलहाल आसार अच्छे नजर नहीं आते।

—रंजना कक्कड़, त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

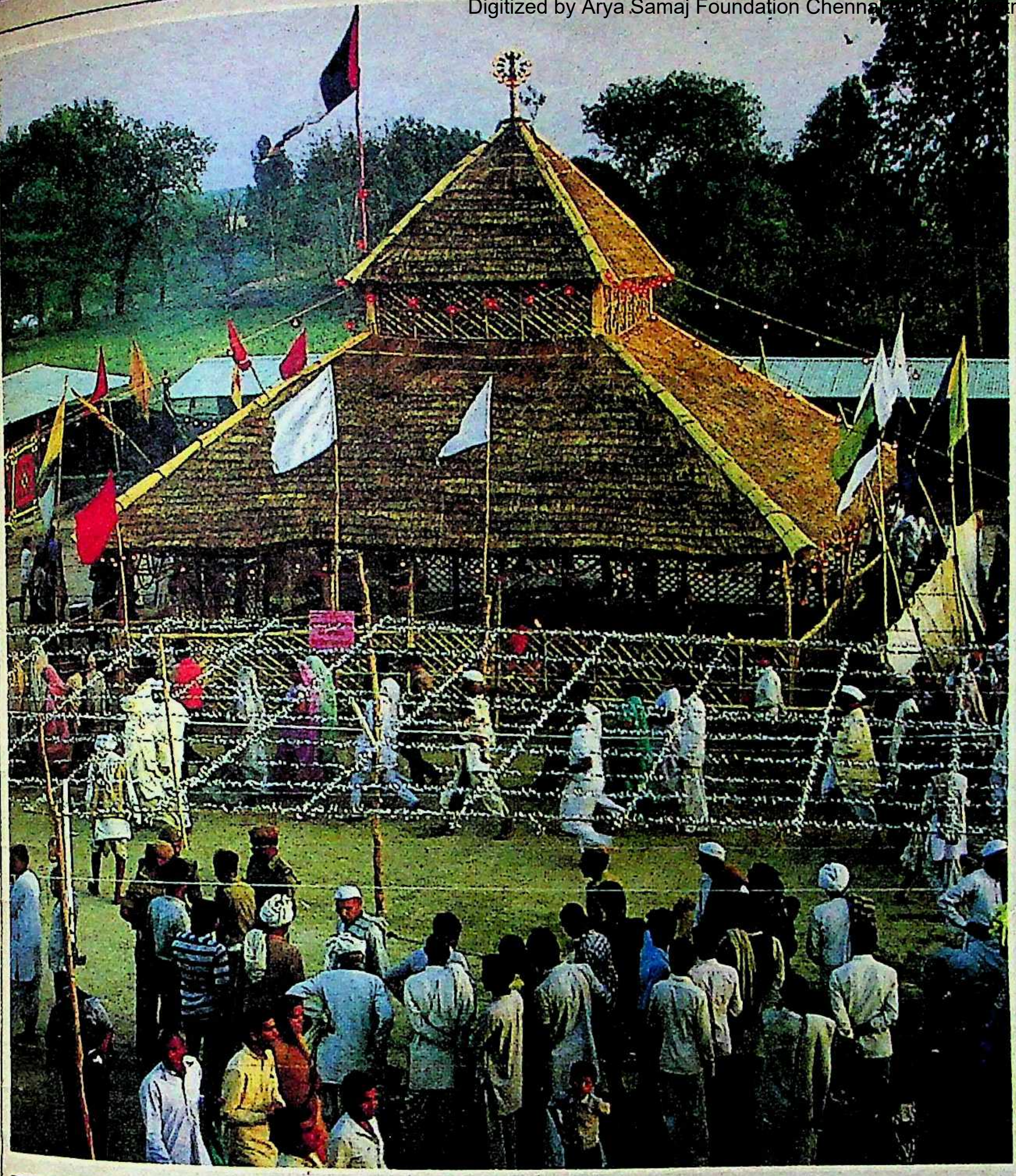

दिवराला सती कांड के बाद गर्हित सती प्रथा को लेकर जो विवादों का महाभारत शुरू हुआ, उसमें नेताओं, समाजसेवियों और धर्माचार्यों ने अपने-अपने ढंग से पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा है। सती प्रथा के कलंक को धोने के लिए सरकार ने सती विरोधी कानून भी बनाया है। लेकिन कानून के बावजूद 'सती,प्रथा नहीं, धर्म हैं' मानने वाले पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ कमर कसकर सती प्रथा का समर्थन करने के लिए मैदान में कूद पड़े, तो शंकराचार्य के जवाब में आर्यसमाज के प्रमुख नेता स्वामी अग्निवेश भी मैदान में आ गये और ललकारने लगे कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ करके साबित करें कि सती प्रथा धर्मसम्मत है। मेरठ के पुरामहादेव गांव में,जहां शंकराचार्य २७ मार्च से 'महारुद्र' यज्ञ (बायें) के बहाने सती समर्थन के लिए 'जन जागरण' (नीचे बायें) कर रहे थे, वहीं २ अप्रैल को शंकराचार्य और अग्निवेश के बीच शास्त्रार्थ भी होना था, पर उसके पहले ही सरकार ने सती विरोधी स्वामी अग्निवेश (नीचे दायें) को तो २०० कार्यकर्ताओं के साथ शांति भंग के आरोप में पुरामहादेव से ५ किमी पहले ही गिरफ्तार कर लिया,लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं दिखायी।

'वेदों का है यह ऐलान, नर नारी हैं एक समान' -जैसे नारों का उद्घोष करते हुए ३१ मार्च को दिल्ली के लाल किले से चले स्वामी अग्निवेश के दल की गिरफ्तारी से फिलहाल शास्त्रार्थ तो टल गया, पर इससे शंकराचार्य और स्वामी अग्निवेश के बीच जारी वाग्युद्ध का अंत नहीं माना जा सकता। शंकराचार्य ने सती प्रथा के विरुद्ध महिलाओं द्वारा उनके मठ (पुरी-उड़ीसा) पर किये गये प्रदर्शन के समय प्रदर्शनकारी महिलाओं को 'वेश्याएं' तक कहा था। जिस धर्म में नारी की पूजा करने का विधान है, उस धर्म के 'रक्षक' शंकराचार्य महाराज का नारी को जिंदा जल मरने की शिक्षा देना और कानून की पक्षधर संभ्रांत नारियों को छिनाल कहना क्या धर्मसम्मत है?

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

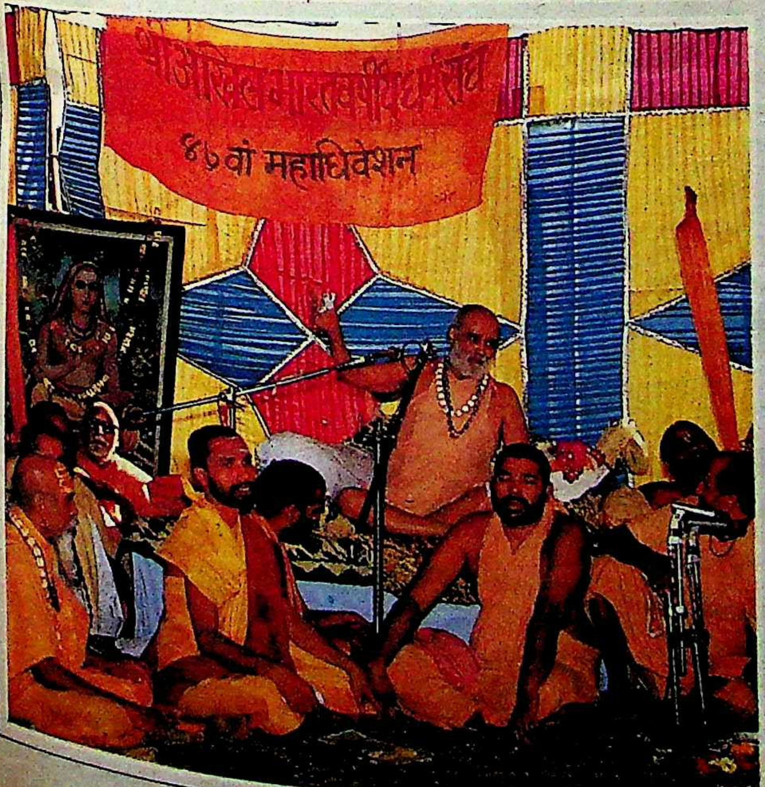

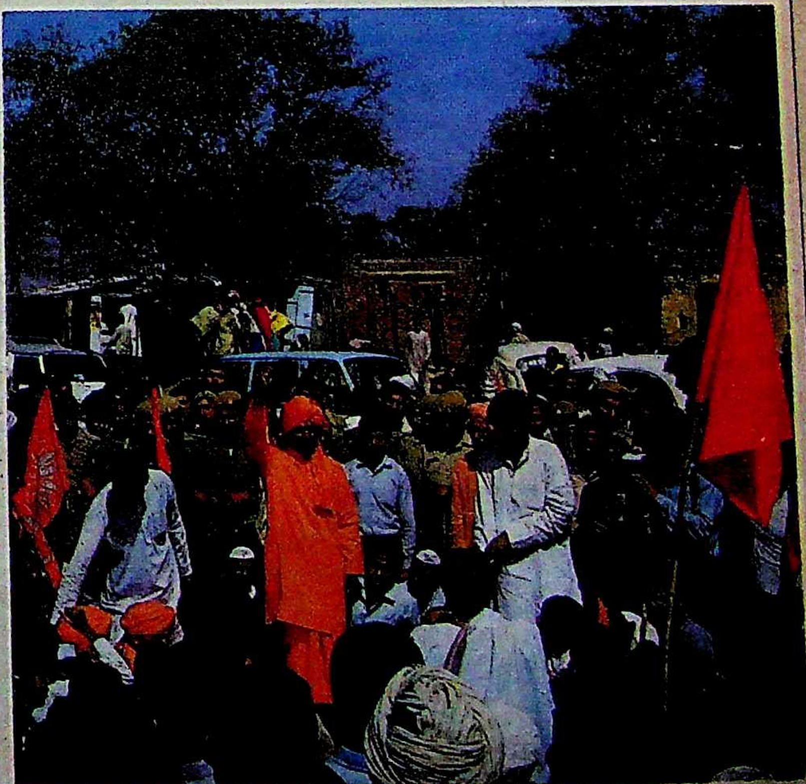

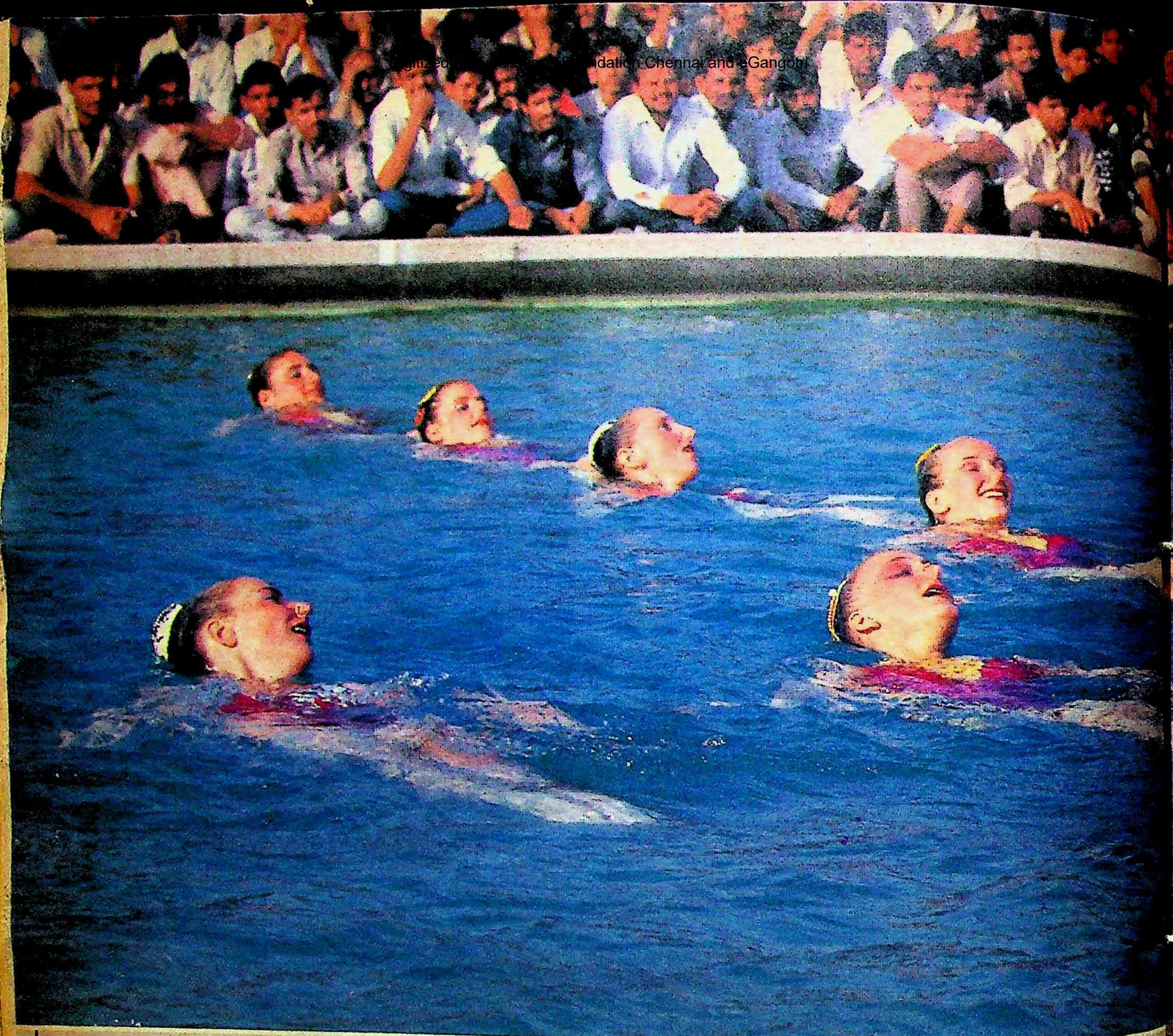

एक वर्ष तक चलने वाले सोवियत महोत्सव में आयी रूसी महिला कलाकारों ने जयपुर में अपनी जल-क्रीड़ाओं के मनोरम और रोमांचक दृश्य प्रस्तुत किये। इन क्रीड़ाओं में इन कलाकारों का संतुलन, तारतम्य, दम-खम और स्फूर्ति देखते ही बनती थी। संगीत की धुनों के साथ ये कलाकार कष्टसाध्य शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से जिस सहजता से मनभावन आकार रचती थीं, वे उनकी जल-साधना के अनुपम उदाहरण थे। हमारे फोटोग्राफर ने कुछ ऐसे ही मोहक दृश्यों को अपने कैमरे में बांधा है, जिन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :

छाया :
गोपाल संगर

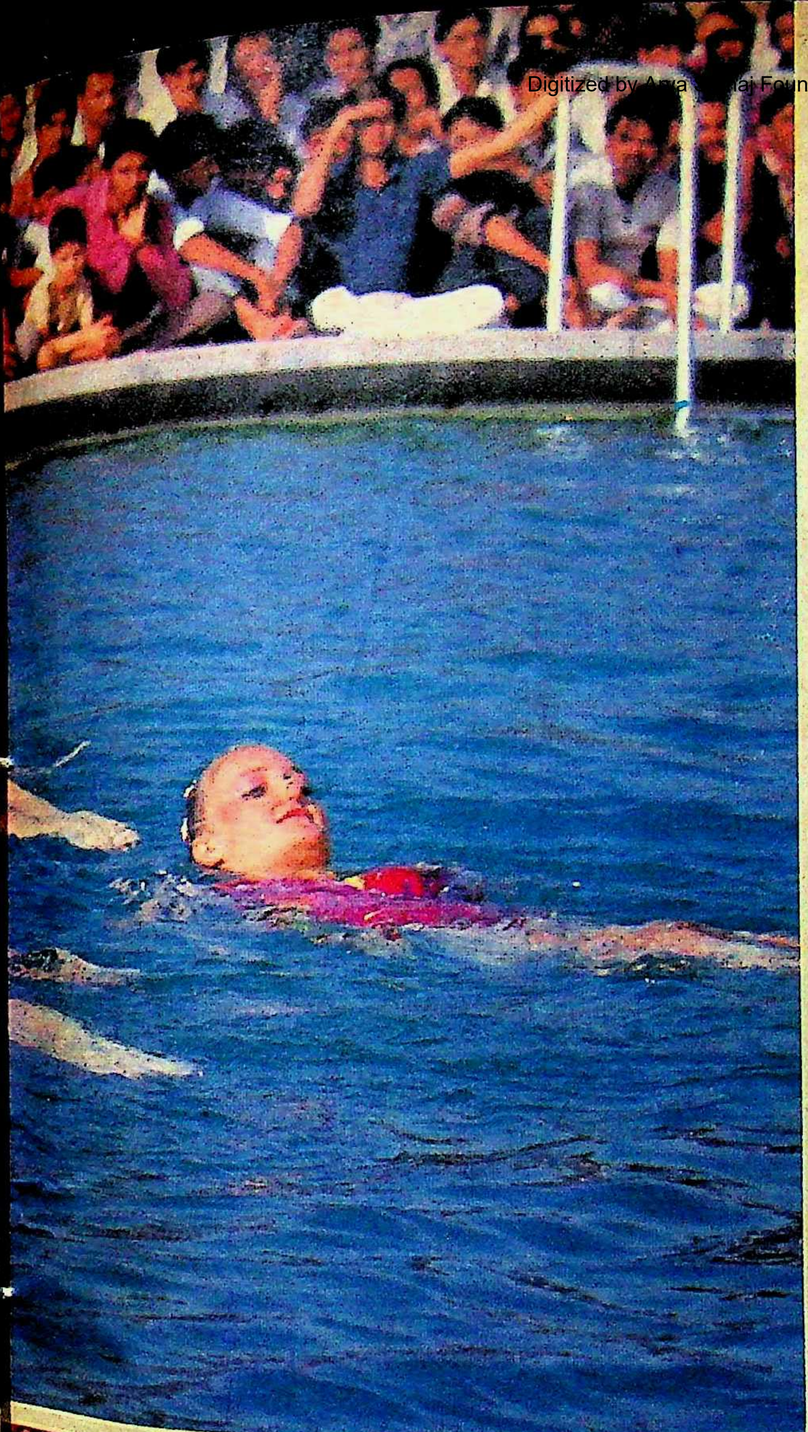

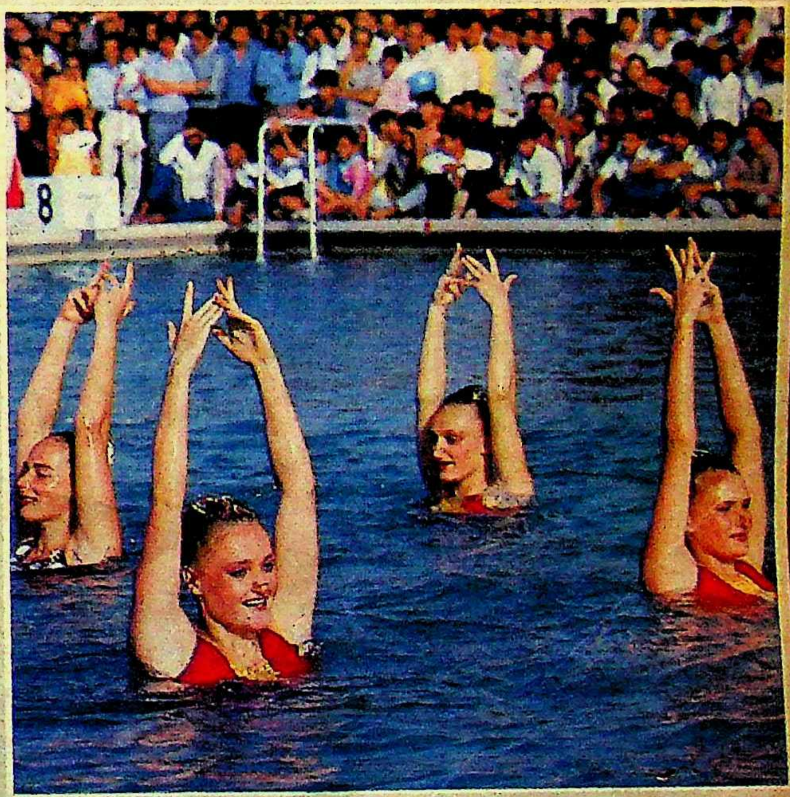

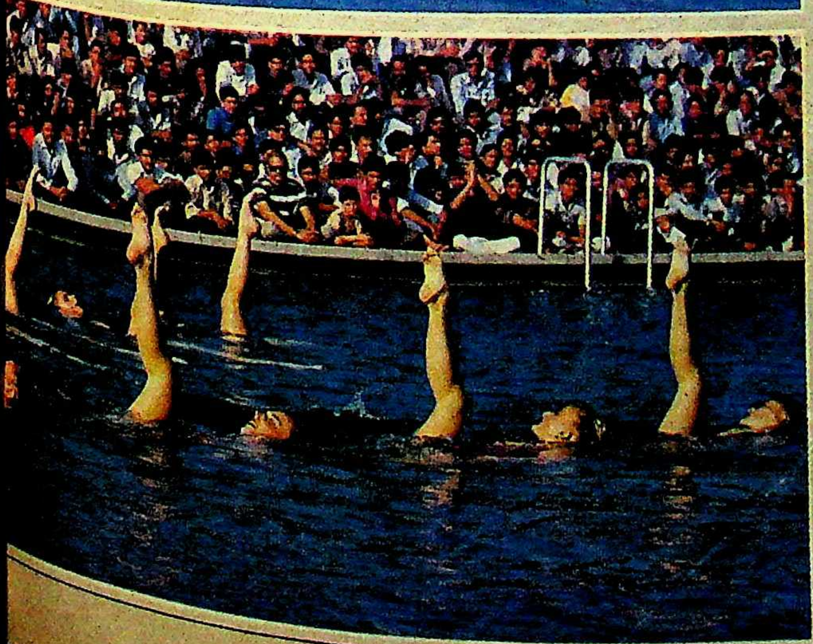

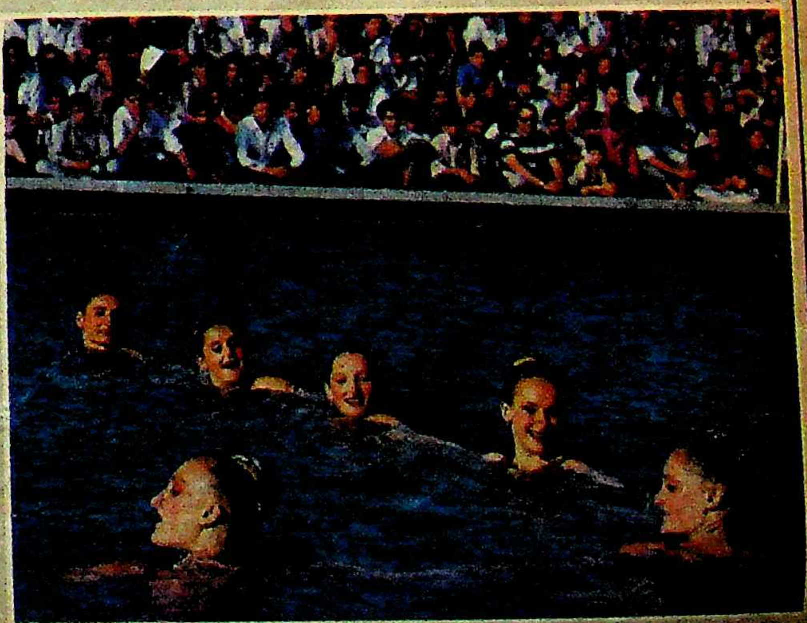

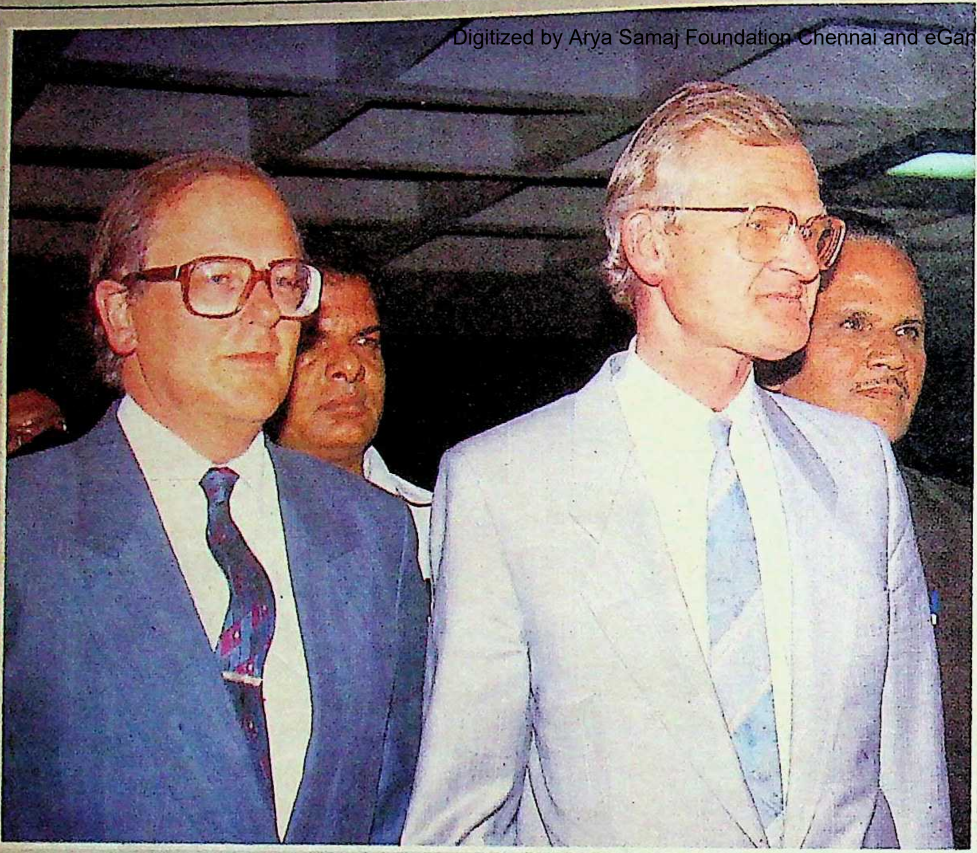

छाया : सीएनएस

बोफोर्स के बहुर्चचित और विवादास्पद पूर्व अध्यक्ष मोरबर्ग और नोबेल इंडस्ट्रीज के मुख्य कानूनी सलाहकार लार्स गोथलिन ७ अप्रैल को नयी दिल्ली में संसद भवन में संयुक्त संसदीय समिति के सामने गवाही देने के लिए जाते हुए। ये दोनों अधिकारी पिछले वर्ष सितंबर में इसी समिति के सामने गवाही देने आये थे।

राजकपूर भारतीय सिनेमा की वह हस्ती हैं जिनके उल्लेख के बिना भारतीय सिनेमा पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। तमाम उपलब्धियों और सम्मानों से ऊपर उठ गये राजकपूर को इस बार फिल्म क्षेत्र के सबसे बड़े 'दादा साहब फालके पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। राजकपूर सम्मानित हुए या 'दादा साहब फालके पुरस्कार' कहना मुश्किल है। पर ४५ वर्ष पूर्व फिल्मी जिंदगी शुरू करने वाले राजकपूर देश और विदेशों के सबसे चहेते कलाकार के रूप में लोकप्रिय रहे हैं।

'बरसात', 'आग', 'आवारा', 'श्री ४२०', 'जागते रहो', 'मेरा नाम जोकर', 'तीसरी कसम' —जैसी क्लासिक फिल्में और 'जिस देश में गंगा बहती है', 'संगम', 'बाबी', 'प्रेम रोग', 'राम तेरी गंगा मैली'—जैसी शुद्ध व्यावसायिक फिल्में बनाने वाले राजकपूर एक ही हैं। हां, यह बहस हो सकती है कि क्लासिक फिल्मों वाले राजकपूर और व्यावसायिक फिल्में बनाने वाले राजकपूर में से असली राजकपूर कौन हैं?

स्वामिभक्त बंदर

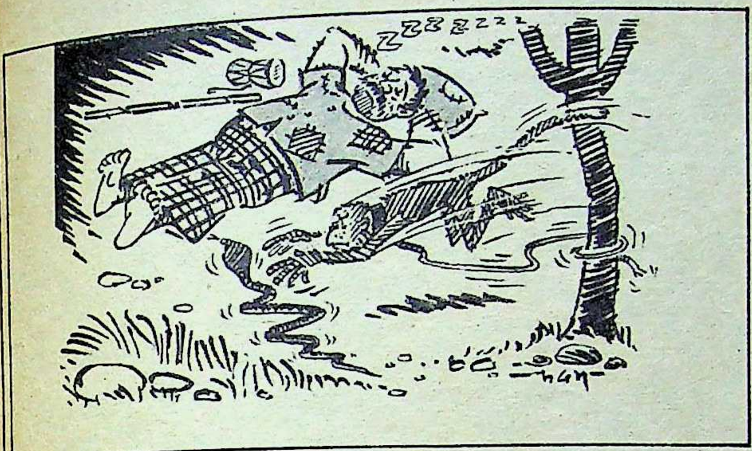

चंचलता के लिए तो बंदर मशहूर हैं, लेकिन वे स्वामिभक्त भी होते हैं, यह आश्चर्य की बात है। वैसे भी अभी तक कुत्ते को ही सबसे अधिक विश्वासपात्र माना जाता रहा है, लेकिन एक बंदर ने भी करिश्मा कर दिखाया है।

हुबली से कुछ दूर लक्ष्मेश्वर के पास ऐसी ही एक घटना घटी। एक मदारी खेल दिखाने के बाद बंदर को पेड़ से बांधकर आराम से सोया हुआ था। उसे क्या पता था कि एक जहरीला सांप उसका काल बनकर आ जायेगा, लेकिन हुआ ऐसा ही। बेचारा बंदर क्या करता, रस्सी से बंधा जो था। लेकिन खेल दिखाने की उसकी ट्रेनिंग काम आ गयी। उसने कुलांचे मार-मार कर किसी प्रकार रस्सी तोड़ी और बंधनमुक्त हो गया। इससे पहले कि वह सांप उसके मालिक को डंसता, बंदर ने उसकी ऐसी-तैसी कर डाली।

फुटबाल खिलाड़ी हाथी

हमारे देश में जब तक क्रिकेट की महामारी नहीं फैली थी, तब तक फुटबाल का बड़ा जोर था। कलकत्ता को तो आज भी फुटबाल का मक्का कह सकते हैं। वहां तो दो टीमों की हार-जीत को लेकर पति-पत्नी में झगड़े तक हो जाया करते हैं। यानी कि वहां आज भी फुटबाल ही लोगों के दिल में बसा हुआ है, फिर भी आदमियों द्वारा फुटबाल का खेला जाना उतनी अहमियत नहीं रखता, जितनी उसकी अहमियत जानवरों के खेलने से बढ़ जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर हमारे देश में जब अन्य प्रांतों में खिलाड़ियों में वह जोशोखरोश नहीं है, तब जानवरों की क्या बात करें? लेकिन दक्षिणी सुमात्रा में तो हाथी भी फुटबाल खेलते हैं। यही नहीं, दक्षिणी सुमात्रा के लैम्पुंग शहर में 'वे कैंबस' नाम का एक ऐसा स्कूल ही है, जहां हाथियों को खेलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मालूम रहे कि कैंबस में इस विद्यालय की स्थापना १९८५ में हुई। इस प्रशिक्षण के तहत उन्हें सलूट करना, कंक्रीट की बेंचों पर बैठना तथा फुटबाल खेलना सिखाया जाता है। उनको तकरीबन ३ महीने तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है जहां फुटबाल की हर बारीकी से उन्हें परिचित कराया जाता है। इस साल इस स्कूल के ४० हाथी खिलाड़ियों में से सबसे अच्छे २५ खिलाड़ियों का चयन बंदर लैम्पुंग में होनेवाली प्रतियोगिताओं के लिए किया गया। मजे की बात तो यह रही कि राष्ट्रपति सुहार्तो ने हजारों फुटबाल प्रेमियों के साथ उनकी हौसला-अफजाई की।

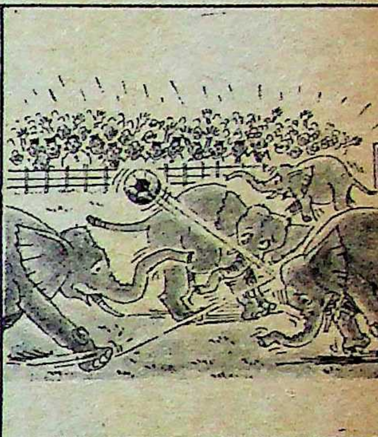

पतंगबाज हवा में

पतंग उड़ाना तो कोई खास बात नहीं, लोगों को पतंगबाजी का शौक होता ही है, लेकिन यदि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ने लगे, तो कोई भी हैरत में पड़ जायेगा। दक्षिणी सेनफ्रांसिस्को की आठ वर्षीय डींड्रा एनरिग के साथ ऐसा ही हादसा हुआ। एनरिग पार्क में पतंग उड़ा ही रही थी कि पास के एक हवाई अड्डे से एक विमान ने उड़ान भरना शुरू किया। हुआ यों कि उस विमान में एनरिग की पतंग की डोरी फंस गयी और उसी विमान के साथ वह तकरीबन तीस मीटर तक उड़ती चली गयी। वह और ऊपर जाती कि बीच में ही एक पेड़ आ पड़ा। टकराने के भय से उसने पतंग की डोर छोड़ दी। फलस्वरूप जमीन पर आ टपकी। लेकिन शुक्र है कि एनरिग को कोई चोट नहीं आयी। उससे यह पूछने पर कि उसकी यह उड़ान कैसी रही, उसने बताया कि वह सिर्फ डरी हुई थी। इस घटना से वहां के अधिकारी अब सचेत हो गये हैं। चूंकि पार्क हवाई अड्डे के अत्यंत नजदीक है, इसलिए अधिकारियों ने वहां पतंगबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है।

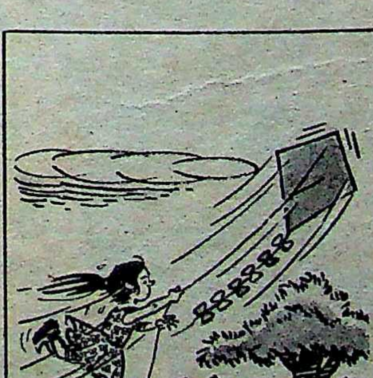

होम करते हाथ जला

कभी-कभी दूसरे की मदद करने के चक्कर में लेने-के-देने पड़ जाते हैं। बात रोड द्वीप की है। बेचारे १६ वर्षीय डेविड इ डुकेट के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हो गया। कहां तो वह अपने १६ वर्षीय मित्र निकोलस लावेल की मदद कर रहा था, कहां निकोलस की जान पर बन आयी। हुआ यों कि निकोलस और डेविड दोनों कंप्यूटर पर काम कर रहे थे कि एकाएक निकोलस को हिचकियां आने लगीं। वह परेशान हो गया। हिचकियां थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। डेविड को एक तरकीब सूझी। वह झट कमरे में गया और अपने पिता की ३८ बोर की पिस्तौल ले आया। उसने सोचा कि यदि वह एकाएक पिस्तौल लावेल के सिर पर लगा दे, तो डर के मारे उसकी हिचकियां बंद हो जायेंगी। उसको क्या पता था कि वह पिस्तौल भरी हुई थी। उसने ज्यों ही उसका घोड़ा दबाया, त्यों ही गोली चल गयी और लावेल को जान से हाथ धोना पड़ा। डेविड को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वह ४०,००० डालर की जमानत पर है। —संयोजन: डा० मुश्ताक अली

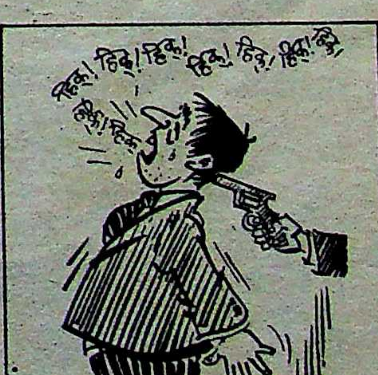
हिक! हिक! हिक! हिक! हिक! हिक! हिक!
हिक! हिक!

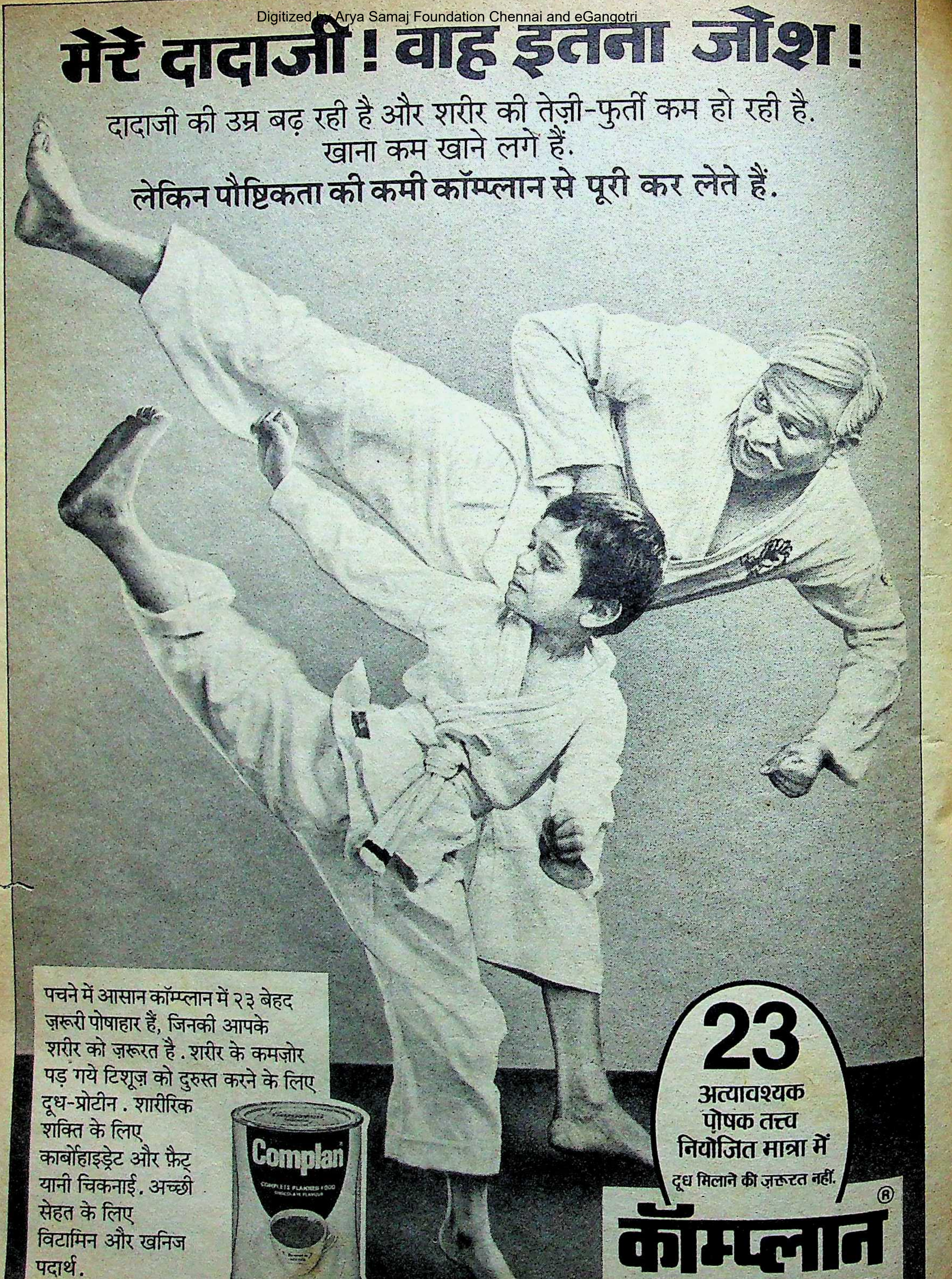

मेरे दादाजी ! वाह इतना जोश !

दादाजी की उम्र बढ़ रही है और शरीर की तेज़ी-फुर्ती कम हो रही है. खाना कम खाने लगे हैं.

लेकिन पौष्टिकता की कमी कॉम्प्लान से पूरी कर लेते हैं.

पचने में आसान कॉम्प्लान में २३ बेहद ज़रूरी पोषाहार हैं, जिनकी आपके शरीर को ज़रूरत है . शरीर के कमज़ोर पड़ गये टिशूज़ को दुरुस्त करने के लिए दूध-प्रोटीन . शारीरिक शक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट और फ़ैट् यानी चिकनाई . अच्छी सेहत के लिए विटामिन और खनिज पदार्थ.

23
अत्यावश्यक
पोषक तत्त्व
नियोजित मात्रा में

दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं.

कॉम्प्लान®
परिपूर्ण नियोजित आहार

GX/47/244/HIN

जनता पार्टी

सुलह या युद्ध विराम ?

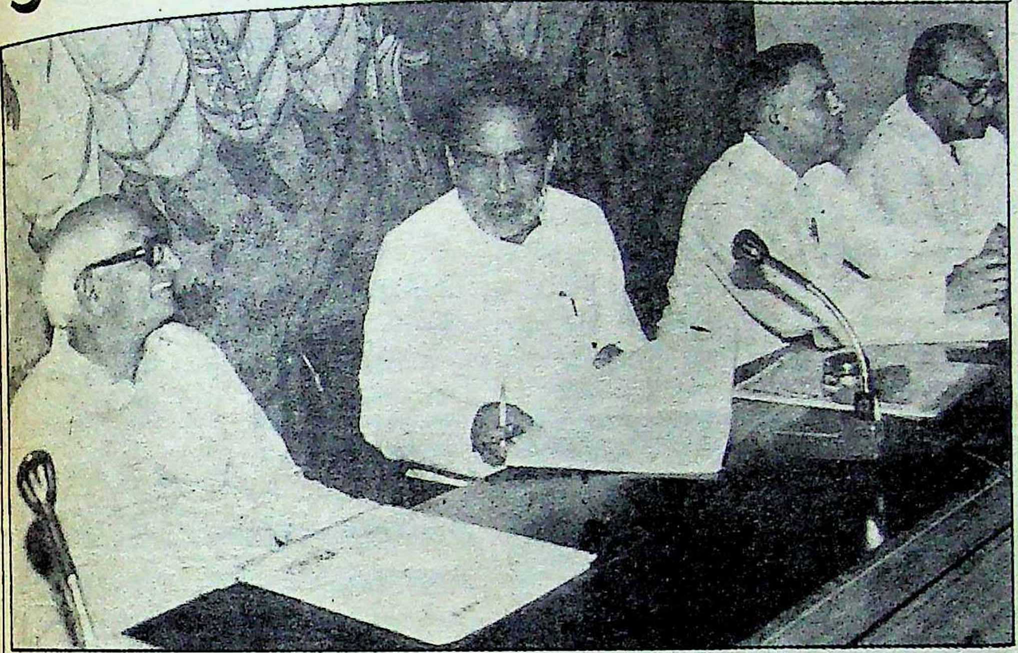

एकता में अनेकता: कार्यकारिणी की एक बैठक में दंडवते, चंद्रशेखर, यशवंत सिन्हा और बीजू पटनायक

हाल में जनता पार्टी में लोकदल-अ के विलय से उठे बवंडर ने राष्ट्रीय मंच से उमड़ते-घुमड़ते हुए कर्नाटक तक पहुंचने के बाद तूफान का रूप धारण कर लिया था। लेकिन तमाम उठापटक के बाद ५ अप्रैल को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव किसी बड़े धमाके की जगह सहजतापूर्वक पारित हो गया। किंतु इसने जहां कुछ प्रश्नों को हल किया, वहीं कुछ नये प्रश्नों, संदेहों, आशंकाओं और खतरनाक मोड़ों का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हेगड़े के इस्तीफा देने की पेशकश इसी ओर संकेत करती है। प्रश्न यह है कि ५ अप्रैल को दो दिग्गज नेताओं की सहसा हुई सुलह है या मात्र युद्ध विराम? इस समूचे प्रकरण में पार्टी द्वारा विपक्षी एकता के लिए किये गये प्रयासों का क्या हश्र होगा?

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अगले दिन ६ अप्रैल को एक जाने-माने जनता सांसद के साथ उनके बंगले के हरे-भरे लान पर 'माया' की विभिन्न विषयों पर बातचीत चल रही थी। चाय की चुस्कियों के बीच बात लौट-घूमकर पार्टी में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उठे हाल के बवंडर से गुजरती हुई दो विवादग्रस्त व्यक्तियों—अध्यक्ष चन्द्रशेखर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े—पर आ टिकी। दोनों नेताओं को करीब से जानने वाले सांसद, सहसा उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी कर बैठे: चन्द्रशेखर को हम गैरईमानदार नहीं कह सकते, किंतु वह निष्ठुर राजनीतिज्ञ हैं। यह राजनीतिक निष्ठुरता उद्देश्यप्राप्ति के लिए आवश्यक है और महात्मा गांधी की रणनीति का भी अभिन्न अंग थी। रामकृष्ण हेगड़े इसके ठीक विपरीत हैं। उन्हें दूध का धुला नहीं कहा जा सकता, किंतु उनमें अपनी पार्टी के अध्यक्ष की दूसरी 'विशेषता' यानी निष्ठुरता का पूर्ण अभाव है।

बात पते की थी। दोनों नेताओं की इन्हीं विशेषताओं और खामियों ने जनता पार्टी में छिड़ी हाल की उठापटक के दौरान निर्णायक भूमिका निभायी। आशानुरूप कम-से-कम इस समय बाजी चन्द्रशेखर के हाथ लग गयी। यह अलग बात है कि पार्टी-सदस्यों सहित राजनीतिक पर्यवेक्षक भी यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या समस्या का वास्तव में अंतिम समाधान हो चुका है अथवा केवल युद्ध विराम हुआ है और आगामी दिनों में युद्ध का बिगुल पुन: बज सकता है।

ज्ञात रहे कि मार्च के शुरू में प्रचारित जनता-लोकदल-अ विलय के समाचार ने पार्टी नेताओं—कार्यकर्ताओं में खलबली मचा दी थी। ५ मार्च को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में हुए विचार-विमर्श के बाद ७ मार्च को चन्द्रशेखर और अजीत सिंह द्वारा जारी किये गये संयुक्त बयान ने जब दोनों दलों के विलय के साथ अजीत सिंह को संयुक्त जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने की घोषणा की, तो सब हक्के-बक्के रह गये। तत्पश्चात घटनाक्रम इतनी तीव्र गति से घूमा कि जनता पार्टी गुटों में विभाजित होती दिखायी दी। असंतुष्ट नेताओं के रूप में सर्वाधिक मुखर बीजू पटनायक और जार्ज फर्नांडिस थे। यद्यपि आम धारणा यही थी कि असंतुष्टों के नेतृत्व में हेगड़े प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। किंतु परोक्ष रूप में वह अपना असंतोष जाहिर करने अथवा बयानबाजी से कोसों दूर रहे।

विद्रोह की स्थिति: अन्य असंतुष्टों में रोष बढ़ता गया और अध्यक्ष पर व्यक्तिगत पत्रों एवं समाचार पत्रों के जरिये दबाव डालने के प्रयास जारी रहे। असंतोष और रोष का प्रमुख कारण विलय नहीं, उसकी प्रक्रिया थी। साथ ही अजीत सिंह का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 'थोपा जाना' भी रोष का कारण था। पार्टी के एक नेता ने 'माया' से कहा, "चन्द्रशेखरजी ने किस अधिकार के तहत अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया अथवा अन्य आश्वासन दिये? यह पार्टी और नेताओं के साथ धोखा था। इन्हीं सब कारणों से पिछली जनता पार्टी टूटी थी। क्या हम एक बार फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी को नष्ट हो जाने दें?" इन्हीं विचारों को पार्टी के मंच पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फौरी बैठक बुलाने की मांग तीव्रतर होती गयी।

बढ़ते उबाल के दौरान १६ मार्च को महाराष्ट्र के पीके अन्नापाटिल ने महाराष्ट्र सदन में एक अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया। इसमें पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य सभी प्रमुख नेताओं—हेगड़े, पटनायक, फर्नांडिस, गुरुपदस्वामी, दंडवते, जयपाल रेड्डी आदि—ने भाग लिया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लगभग तीन घंटे चलने वाली इस बैठक में बहस गरमागरम रही और चन्द्रशेखर को अनेक आक्षेपों-आरोपों का सामना करना पड़ा। अन्तत: उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाने का ऐलान किया। असंतुष्टों को लगा कि विजय पताका उनके हाथ आ गयी।

किंतु शीघ्र ही उनके सपनों के महल ढह गये। उनकी समझ में आ गया कि राजनीति के पुराने और जाने-माने खिलाड़ी चन्द्रशेखर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के उनके निर्णय के पीछे छिपी यह जानकारी थी कि उनके समर्थकों का बहुमत है और असंतुष्टों के लिए न केवल हार का मुंह देखना अपरिहार्य है, वरन जनता-लोकदल-अ के विलय के साथ अजीत सिंह के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी उनकी स्वीकृति की मोहर लगने वाली है। जाहिर है, विद्रोही नेता अपने ही रचे जाल में फंसने के लिए बाध्य हो गये थे।

बस क्या था! आव देखा न ताव, सबने स्थिति से उबरने के लिए दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिये। सबसे सीधी और सरल दिशा दिखायी दी व्यापक एकता के प्रयासों में। अतः उसी मार्ग पर चल पड़े।

नया मोड़: यह कहना कठिन है कि पहल किसने की। अजीत सिंह की विलय संबंधी सफलता से क्षुब्ध, मार्ग में रोड़े अटकाने और विपक्ष की लगाम अपने हाथ में लेने हेतु देवीलाल ने, चन्द्रशेखर को येन-केन प्रकारेण मात देने की धुन में असंतुष्ट जनता नेताओं ने अथवा वीपी सिंह के धीमे पड़ते अभियान को नयी गति प्रदान करने के लिए जनमोर्चा ने? देवीलाल के चंडीगढ़ से जारी किये गये वक्तव्य ने यह समाचार आग की तरह फैला दिया कि विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के मध्य एकीकरण पर व्यापक चर्चा हुई है, जिससे वामपंथियों को छोड़ अन्य सभी दलों के साथ आने की संभावना बढ़ गयी है। आश्चर्य की बात यह थी कि विचार-विमर्श में भाग लेने वाले अनेक नेताओं में जनता पार्टी की तरफ से बीजू पटनायक और हेगड़े थे, न कि पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर। किंतु इससे अधिक विस्फोटक समाचार एक तो यह था कि इस एकीकृत गुट के नेतृत्व की बागडोर वीपी सिंह के हाथ में सौंपी जायेगी। साथ ही संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं देवीलाल संभालेंगे। दूसरे एकीकरण की घोषणा और व्यवस्था ५ अप्रैल से पहले हो जायेगी।

मतलब साफ था। जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व की गयी घोषणा न केवल बैठक को निरर्थक बना देती, बल्कि चन्द्रशेखर और अजीत सिंह को हाशिये पर डाल देने में भी सफल सिद्ध होती। अतः चन्द्रशेखर खेमे में खलबली मच जाना नितान्त स्वाभाविक था। पासा-पलटने के आसार सामने थे। स्थिति पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए रणनीति में फौरी परिवर्तन आवश्यक हो गया। चन्द्रशेखर और अजीत सिंह ने वक्तव्य जारी कर दिया कि उन्हें विपक्षी एकता की बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। उनका इतना कहना एकीकरण की कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए काफी था।

चन्द्रशेखर को वास्तव में जानकारी थी या नहीं यह विवादास्पद रहा है। यद्यपि चन्द्रशेखर खेमा इससे लगातार इनकार करता रहा है, पर हेगड़े-समर्थकों का दावा है कि हेगड़े ने बातचीत का कदम न केवल चन्द्रशेखर की जानकारी में, बल्कि उनके कहने और आशीर्वाद के बाद ही उठाया था। प्रश्न यह है कि आदेश-आज्ञा देने के बाद चन्द्रशेखर मुकर क्यों गये?

विश्वसनीय सूत्रों से 'माया' को पता चला है कि व्यापक विपक्षी एकता का मुद्दा स्वयं चन्द्रशेखर ने गत १६ मार्च को महाराष्ट्र सदन की बैठक के दौरान चौतरफा आक्रमण से घिरे और त्रस्त होने पर कदाचित अपनी जान छुड़ाने हेतु उठाया था। उस समय उन्होंने यह कहा कि यद्यपि वह लोकदल-अ से विलय और अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, किंतु यदि विस्तृत एकता का [illegible] तो वह अथवा अजीत सिंह बाधा नहीं बनेंगे। इसी के तहत उन्होंने अन्य दलों से बातचीत कर किसी नतीजे पर पहुंचने की बात स्वीकारी थी।

मुकर क्यों गये?: बाद में मन और बयान बदलने के पीछे कई कारण पाये जाते हैं। एक तो ठंडे दिमाग से सोचने पर चन्द्रशेखर ने यह समझ लिया होगा कि यदि इस प्रकार की एकता हो गयी; तो उन्हें न तो लेशमात्र श्रेय मिलेगा, न ही कोई महत्ता। दूध की मक्खी की तरह निकाल कर उन्हें फेंक दिया जायेगा। दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह का विपक्ष में बढ़ता प्रभुत्व आसमान छूने लगेगा—इसकी परिकल्पना मात्र ही निश्चय को डिगाने के लिए पर्याप्त थी। दुनिया को दिखाने के लिए कहा या किया चाहे कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के विपक्ष और देश में बढ़ते प्रभाव ने चन्द्रशेखर के मानस और अहंकार को भारी ठेस पहुंचायी है। कारण स्पष्ट है। विपक्ष की लम्बी लड़ाई चन्द्रशेखर ने लड़ी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो सत्ता का सुख छोड़ विपक्षी मैदान में बस कल ही उतरे हैं। विजय का सेहरा उनके माथे बंधे यह चन्द्रशेखर कैसे गवारा करते। यही नहीं, राजनीति का यह नया मोड़ उनके भावी प्रधानमंत्री होने के दावे और संभावना को निश्चय ही चकनाचूर कर देने में सहायक होता, इसलिए पुराने सेनापति की अवहेलना से उत्पन्न द्वेष और क्रोध अस्वाभाविक नहीं।

रामकृष्ण हेगड़े

इसके अतिरिक्त जिस ताबड़तोड़ जल्दबाजी से बातचीत शुरू हुई और घोषणाएं होने लगीं, उन्होंने पार्टी नेताओं की नीयत की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया। जो नेता कल तक स्वयं चन्द्रशेखर द्वारा लोकदल-अ के विलय को जल्दबाजी में लिया फैसला करार दे रहे थे, उनके द्वारा जिस तत्परता से बातचीत की गयी, वह निस्संदेह अपमानजनक ही नहीं, षड्यंत्र का भी द्योतक थी। अध्यक्षजी के रोष का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपराधियों को सबक सिखाने की ठान ली। एक ओर 'हवा में अधिक ऊंचा उड़ने' का प्रयास करने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के पर कतरने का दृढ़ निश्चय था, तो दूसरी ओर 'कलिंगा के राजा बीजू पटनायक' को रास्ते पर लाने का। कर्नाटक में विद्रोह ने सुअवसर शीघ्र ही प्रदान कर दिया।

चन्द्रशेखर के मानस और उनकी कार्यशैली से परिचित पर्यवेक्षकों और राजनीतिज्ञों की धारणा है कि विद्रोह की आग भले ही चन्द्रशेखर ने स्वयं न लगायी हो, किंतु कम-से-कम उसको हवा जरूर दी होगी। विद्रोह के लिए चुना गया वक्त ऐन दिल्ली में विलय को लेकर उभरे विवाद के समय भी इस धारणा की पुष्टि करता है। किंतु स्वयं चन्द्रशेखर आरोप सुन आगबबूला हो, उसे सरासर निराधार करार देते हैं। (देखिए साक्षात्कार) उनके समर्थक तो एक कदम आगे बढ़ यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में चन्द्रशेखर का हाथ रहा हो, उसे हटाने का प्रयास वह क्यों करेंगे?

संबंधों में बिगाड़: एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार चन्द्रशेखर-हेगड़े संबंधों में उतार १९८४ के लोकसभा चुनाव के बाद शनैः-शनैः तब आरंभ हुआ, जब न केवल जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, बल्कि स्वयं चन्द्रशेखर को अपने गढ़ बलिया में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके कुछ समय पश्चात १९८५ में कर्नाटक में हुए चुनावों में आसानी से प्राप्त विजय ने चन्द्रशेखर-हेगड़े संबंधों में रातोरात आशातीत परिवर्तन ला दिया। जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मीडिया तो उन्हें उछाल ही रहा था, किंतु स्वयं हेगड़े इस गलतफहमी का शिकार हो गये कि भावी प्रधानमंत्री-पद के वह अकेले दावेदार हैं। कहा जाता है कि इसके बाद पार्टी अथवा अध्यक्ष के सलाह-मशविरे से उन्होंने कन्नी काट ली और कर्नाटक को अपनी निजी जागीरदारी बना दिया। जाहिर है कि चन्द्रशेखर इस अपमान को खून का घूंट समझकर पी गये। किंतु मन के किसी कोने में बदले की भावना अवश्य ही घर कर गयी थी।

चंद्रशेखर-हेगड़े संबंधों में उतार १९८४ के लोकसभा चुनाव के बाद शनैः-शनैः तब आरंभ हुआ, जब न केवल जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, बल्कि स्वयं चंद्रशेखर को अपने गढ़ बलिया में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके कुछ समय पश्चात १९८५ में कर्नाटक में हुए चुनावों में आसानी से प्राप्त विजय ने चंद्रशेखर-हेगड़े संबंधों में रातोरात आशातीत परिवर्तन ला दिया।

चन्द्रशेखर समर्थकों का दावा है कि बदला लेने का कोई प्रयास उन्होंने न पहले किया न अब। उनके अनुसार चन्द्रशेखर को उकसाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि देवगौड़ा व अन्य कई सदस्य पहले ही खार खाये बैठे थे। एक तो देवगौड़ा स्वयं मुख्यमंत्री बनने के आकांक्षी थे, दूसरे हाल में उनके संबंध में उभरे आरोपों और जांच ने आग में घी का काम किया। कर्नाटक में सन्तुलन वैसे भी गड़बड़ाया हुआ था और जब राष्ट्रीय स्तर पर सन्तुलन बिगड़ा और विद्रोह की चिनगारियां भड़कने लगीं, तो देवगौड़ा और उनके सहयोगियों को शह मिल गयी। आवश्यकता केवल सुअवसर प्राप्त करने की थी।

यह उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गया। राम जेठमलानी को राज्यसभा का टिकट देने का विरोध इतना तीव्र हो गया कि ऐन मतदान के दिन प्रातः हुई विधायक दल की आधिकारिक बैठक में केवल ४० सदस्य शामिल हुए। ६० से अधिक असंतुष्ट पार्टी विधायकों को मतदान के लिए रजामंद करने हेतु सांसद मधु दंडवते को अथक प्रयास करना पड़ा। तब कहीं जाकर मतदान समाप्त होने के १५ मिनट पूर्व ये विधायक मतदान के लिए पहुंचे।

एक तो देवगौड़ा स्वयं मुख्यमंत्री बनने के आकांक्षी थे, दूसरे हाल में उनके संबंध में उभरे आरोपों और जांच ने आग में घी का काम किया। कर्नाटक में संतुलन वैसे भी गड़बड़ाया हुआ था और जब राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बिगड़ा और विद्रोह की चिनगारियां भड़कने लगीं, तो देवगौड़ा और उनके सहयोगियों को शह मिल गयी। आवश्यकता केवल सुअवसर प्राप्त करने की थी।

कहने को तो विरोध का मुख्य कारण यह था कि पार्टी के लोग न तो राम जेठमलानी को जनता पार्टी का सदस्य मान रहे थे न उन्हें कर्नाटक निवासी। किंतु हेगड़े-समर्थकों के अनुसार सारा खेल इस नीयत से खेला जा रहा था कि आधिकारिक उम्मीदवार को हरा दिया जाये और उसके बाद मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग देवगौड़ा को उस पद पर स्थापित कर दिया जाये। अन्तिम घड़ी में निर्णय में जो परिवर्तन हुआ, उसके लिए चन्द्रशेखर खेमे के अनुसार काफी प्रयास करना पड़ा था। महासचिव यशवन्त सिन्हा के अनुसार, "प्रयास विद्रोह दबाने के लिए किये गये थे, भड़काने के लिए नहीं।" उनके इस दावे का समर्थन हेगड़े खेमे के एक वरिष्ठ सांसद ने भी यह कह कर किया, "पार्टी अध्यक्ष ने विद्रोह भड़काया नहीं, किंतु उसके भड़क उठने पर अपने हितों के लिए भरपूर लाभ जरूर उठाया।"

जहां तक लाभ उठाने का प्रश्न है, कर्नाटक में विद्रोह का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। एक ओर चौतरफा घिरे अध्यक्ष को बड़ी सफाई से बच निकलने का मौका प्रदान कर दिया, दूसरे मुख्यमंत्री को इतना अधिक उलझा दिया कि वह विपक्षी एकता की अपनी कोशिशों को तिलांजलि देकर अपनी गद्दी बचाने के प्रयास में जुट गये।

विद्रोह के परिणामों से अवगत होने में हेगड़े को विशेष समय या बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं थी। सरकार और कुरसी बचाने के लिए सुलह जरूरी थी, यह तो ज्ञात था ही। साथ ही यह भी कि इसका स्तर राष्ट्रीय करना होगा। इसी जानकारी के तहत उन्होंने चन्द्रशेखर से मिलने का निश्चय और प्रयास आरंभ कर दिया।

यद्यपि हेगड़े खेमा इस बात का जोर-शोर से प्रचार कर रहा है कि बम्बई में हुई हेगड़े-चन्द्रशेखर मुलाकात आकस्मिक थी, किंतु 'माया' को जानकार सूत्रों से पता चला है कि वह पूर्वनियोजित थी, वह भी स्वयं हेगड़े के आग्रह पर। मुलाकात बम्बई के कारमाइकल रोड पर 'ऊषा किरण' भवन में जयंत मल्होत्रा, जो दोनों नेताओं के पुराने मित्र हैं, के निवास स्थान पर हुई। हेगड़े बम्बई पहले ही पहुंच कर इंतजार कर रहे थे। चन्द्रशेखर सांताक्रुज हवाई अड्डे से सीधे 'ऊषा किरण' पहुंचे और दोनों नेताओं के मध्य लम्बी बातचीत हुई। सारे गिले-शिकवे पूरे होने के बाद प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मोटे तौर पर यह तय हुआ कि हेगड़े आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकदल-अ के विलय और अजीत सिंह के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के प्रस्तावों को निष्कंटक पारित हो जाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे और फिलहाल व्यापक एकता के अपने प्रयासों को लगाम देंगे। बदले में देवगौड़ा और उनके साथियों को चन्द्रशेखर समझा-बुझाकर विद्रोह समाप्त करने के लिए मना लेंगे।

देवगौड़ा

चन्द्रशेखर के बम्बई से लौटने के पूर्व ही उनके समर्थकों के खिले चेहरे इस बात की मूक गवाही दे रहे थे कि ५ अप्रैल की बैठक में मात्र औपचारिकता बरती जानी थी। हुआ भी ऐसा ही। केवल ४५ मिनट में संपूर्ण हो जाने वाली बैठक में लोकदल-अ और राष्ट्रीय संजय मंच के जनता पार्टी में विलय प्रस्ताव के अतिरिक्त अजीत सिंह के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रस्ताव भी पेश और पारित हुए। प्रथम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अध्यक्ष चन्द्रशेखर को अधिकार दिया कि वह एक समिति का गठन कर अगले सांगठनिक चुनावों के पूर्व एकजुटता की प्रक्रिया का निर्माण करें। दूसरा, पार्टी विपक्ष की व्यापक एकजुटता के सभी प्रयास जारी रखेगी। अपेक्षित बड़े धमाके की जगह जिस सहजता से कार्य संपन्न हुआ, वह सराहनीय था और उसकी सफलता का सेहरा चन्द्रशेखर के सिर था जो यह सिद्ध करने में सफल हो गये थे कि पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है।

विस्फोट एक दिन पश्चात तब हुआ, जब विभिन्न सम्पादकीय टिप्पणियों में विलय की चर्चा के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें प्रकाशित हुईं। मसलन चन्द्रशेखर एक मई को त्यागपत्र दे देंगे। अजीत सिंह का कार्यकारी अध्यक्ष पद बरकरार रहेगा, किंतु अगले सांगठनिक चुनावों तक एक अन्तरिम अध्यक्ष की व्यवस्था की जायेगी। ५ सदस्यों की एक समिति बनेगी, जिसमें हेगड़े, चन्द्रशेखर, मधु दंडवते, अजीत सिंह, सत्य प्रकाश मालवीय होंगे और यह समिति अंतरिम अध्यक्ष का चयन करेगी।

गुटबंदी : चन्द्रशेखर-अजीत सिंह गुटों पर तो जैसे वज्रपात हो गया। पार्टी पुनः दो गुटों में विभाजित हो, सफाई कार्य में जुट गयी। चन्द्रशेखर गुट समाचार को मिथ्या करार दे खंडन करने लगा। सबूत के तौर पर उन्होंने पारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें इसका कहीं कोई जिक्र न था। इनके अनुसार यह प्रचार हेगड़े खेमे की [illegible] थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अध्यक्ष चन्द्रशेखर को एक ओर तो पदत्याग करने के लिए बाध्य करना था, दूसरी ओर मनपसन्द अन्तरिम अध्यक्ष बैठाकर अजीत सिंह के मंसूबों पर पानी फेर देना था। स्वयं चन्द्रशेखर के रोष का ठिकाना न था। लोकदल-अ और अजीत सिंह के सम्मुख उनकी स्थिति अति नाजुक हो गयी थी।

हेगड़े गुट आसानी से हार मानने की मनःस्थिति में नहीं था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने 'माया' को बताया, "यद्यपि यह सही है कि पारित प्रस्ताव में इन मुद्दों की चर्चा नहीं है, किंतु बैठक की पूर्व संध्या को हुई लम्बी बातचीत में इन सभी मुद्दों पर गम्भीर, यदाकदा गर्म विचार-विमर्श हुआ था और ये सभी बातें स्वीकार कर ली गयी थीं। यही कारण है कि औपचारिक बैठक इतनी सहजतापूर्वक संपन्न हुई थी। उनका दावा था कि चन्द्रशेखर का बदला रुख अजीत गुट के दबाव के कारण हुआ था।

फिलहाल स्थिति युद्ध विराम की ही प्रतीत

साक्षात्कार/ चन्द्रशेखर

न सुलह हुई है, न युद्ध विराम

माया :फिलहाल जनता पार्टी में सुलह हुई है या युद्ध विराम?

शेखर : न सुलह हुई है न युद्ध विराम। जनता पार्टी ने उस प्रक्रिया को पूरा किया है, जिसकी कुछ लोग मांग कर रहे थे। मैं समझता था कि इसके तकनीकी पहलू में न जाकर, सबकी सलाह से यह कार्य कर लिया जाये।

माया : यह तो आप मानेंगे ही कि विवाद था। उसका समाधान कैसे हुआ?

शेखर : कुछ लोग ऐसा समझते थे कि विलय के लिए मैंने जो कदम उठाया था, वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पूछे बिना उठाया था। मैंने अजीत सिंह को जो पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि उसे मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने रखूंगा। लेकिन जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, तो कुछ मित्रों ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसको मानकर मैंने ऐलान किया था। किंतु कुछ लोगों ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करनां आवश्यक है। किंतु यह बात उन्होंने मुझसे नहीं कही, अखबारों से कही। यह विवाद जब उजागर हुआ, तब मैंने कहा कि क़ानूनी और संवैधानिक पहलुओं में न जाकर मैं औपचारिकताएं पूरी करूंगा और मैंने वे औपचारिकताएं पूरी कीं।

माया : समाधान क्या विशेष शर्तों पर हुआ है?

शेखर : शर्तें वही हैं जो प्रस्ताव में लिखी हुई हैं। इसके अलावा कोई शर्त नहीं।

माया : क्या आप एक मई को पद त्याग कर रहे हैं?

शेखर : मैंने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। यह फैसला हम तब करेंगे, जब कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह से बात कर लेंगे। मैं उनके बिना न तो किसी को आश्वासन देता हूं, न कोई कदम उठाता हूं।

माया : पांच सदस्यीय समिति और अंतरिम अध्यक्ष की जो बात उठी है, उसमें कितनी सचाई है?

शेखर : इसमें वास्तविकता इतनी है कि समिति बनाने का अधिकार मुझे दिया गया है। मैं बातचीत करने के बाद ही इस सिलसिले में कोई फैसला करूंगा, वैसे मैं कोई भी ऐसा काम करने वाला नहीं हूं, जिसमें अजीतं सिंह की सहमति न हो।

माया : अंतरिम अध्यक्ष बनाने की बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

शेखर : जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनसे यह प्रश्न पूछिए। मैंने तो कभी ऐसी बात कही नहीं।

माया : उन लोगों का कहना है कि आपने आश्वासन दिया है और इस बारे में कार्यकारिणी की बैठक में पेश प्रस्ताव का आपने खंडन नहीं किया है।

शेखर : जिन्होंने पेश (प्रस्ताव) किया है, वे जानें। यदि कुछ लोगों को आश्वासन मिला है, तो वह पूरा करा लेंगे। लेकिन मेरे हर आश्वासन की परिधि यह है कि जो कुछ होगा, अजीत सिंह की सहमति से होगा।

माया : क्या यह विडंबना नहीं है कि जिस जनता पार्टी ने विपक्षी एकता का आह्वान किया था, उसी में नये मोर्चे खुल गये हैं?

शेखर : मुझे नहीं मालूम, कहां मोर्चे खुल गये हैं। अखबारवालों के दिमाग में मोर्चे हैं। वे अपने दिमाग में खयाली पुलाव पकाते रहते हैं। कागज के किले बनाते रहते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

माया : इस आरोप में कितनी सचाई है कि जो असंतुष्ट हैं उन्हें आपने सबक सिखाने के लिए नाटक किया है। मसलन रामकृष्ण हेगड़े को?

शेखर : रामकृष्ण हेगड़े कभी मुझसे असंतुष्ट नहीं रहे और न उनका आज तक मतभेद रहा। मैं किसी को सबक सिखाने के लिए राजनीति में नहीं हूं। मैं नया समाज बनाने के लिए राजनीति में हूं। कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, उसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जो भी विवाद है, वह आपसी विचार-विमर्श से दूर हो जायें, मैं ऐसा मानता हूं। राजनीतिक लोग या अखबार वाले मेरी बात को बदल नहीं सकते। न मुझ पर प्रभाव डाल सकते। ऐसे प्रचारों को मैं कुत्सित प्रचार मानता हूं। ये १५ वर्षों से मेरे खिलाफ किये जा रहे हैं। लेकिन इनका मेरे राजनीतिक भविष्य पर न कोई प्रभाव पड़ा है, न पड़ेगा। ■

होती है। इस दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने किले मजबूत करने और नयी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। विडंबना यह है कि इस समस्त प्रक्रिया में विवाद के केन्द्र बिन्दु तीसरे पक्ष लोकदल-अ की पूर्ण अवहेलना की गयी है। इसके अध्यक्ष अजीत सिंह जो अपना नाम, झंडा, डंडा सब कुछ समर्पित कर जनता पार्टी में विलय के लिए तैयार हो गये, उनकी उपेक्षा-अवहेलना जोर-शोर से जारी है, खासकर चन्द्रशेखर-विरोधी खेमे द्वारा। इसका दूरगामी प्रभाव घातक और विघटनकारी हो सकता है, क्योंकि लोकदल-अ के कार्यकर्ताओं व नेताओं के बीच हौले से जलती क्रोधाग्नि कब दावानल का रूप धारण कर ले, कहा नहीं जा सकता।

अजीत सिंह के एक करीबी सूत्र ने 'माया' से बातचीत में कहा, "हम अभी तक अपने होंठ सिले हुए हैं, यह हमारी भलमनसाहत की एक निशानी है। किंतु हमारे बरदाश्त की भी एक सीमा है। हम भी तो अपनी कार्यकारिणी बुलाकर भला-बुरा कह सकते थे। किंतु विपक्षी एकता को मद्देनजर रख

जार्ज फर्नांडिस

७ मार्च को चंद्रशेखर और अजीत सिंह द्वारा जारी किये गये संयुक्त बयान ने जब दोनों दलों के विलय के साथ अजीत सिंह को संयुक्त जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने की घोषणा की, तो सब हक्के-बक्के रह गये। तत्पश्चात घटनाक्रम इतनी तीव्र गति से घूमा कि जनता पार्टी गुटों में विभाजित होती दिखायी दी। असंतुष्ट नेताओं के रूप में सर्वाधिक मुखर बीजू पटनायक और जार्ज फर्नांडिस थे।

साक्षात्कार/अजीत सिंह

लोकदल-ब भी शीघ्र हमारे साथ आयेगा

माया : जनता पार्टी में समझौते से आप कितने संतुष्ट हैं ?

अजीत : जनता पार्टी ने विलय को सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की है और इसका सभी ने स्वागत किया है। इसके अलावा अखबारों आदि के जरिए जो शोर मचाया गया था कि विलय संबंधी अपनाया गया तरीका गलत है, वह भी अब समाप्त हो गया है।

माया : चन्द्रशेखर के पद त्यागने और नया पार्टी अध्यक्ष चुने जाने तक एक नये अंतरिम अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। यह क्या आप में विश्वास की कमी का द्योतक नहीं है ?

अजीत : जनता पार्टी कार्यकारिणी के प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जो लोग अखबारों में जानबूझ कर छपवा रहे हैं, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रस्ताव में न तो अंतरिम अध्यक्ष का कोई उल्लेख है और न समिति का।

माया : आपके विचार से पार्टी चुनाव कब तक होंगे ?

अजीत : अब तो विलय हो गया है। जनता पार्टी कार्यकारिणी ने तो इसकी पुष्टि कर दी है और पार्टी ने यह कार्य मुझे सौंपा है। दोनों की कार्यकारिणी को बुलाकर एक संयुक्त कार्यकारिणी बैठक करनी होगी। जो तदर्थ संयुक्त राष्ट्रीय परिषद है, उसकी एक मीटिंग होगी। उसमें इसकी पुष्टि की जायेगी। उसके बाद ही चुनाव की बात होगी।

माया : विलय और आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के प्रश्न पर विवाद शायद नहीं है, विवाद आपको अध्यक्ष बनाने को लेकर है।

अजीत : इसमें विवाद की क्या बात है। कोई भी उम्मीदवार बन सकता है। चुनाव तो संयुक्त राष्ट्रीय परिषद ही करेगी। वैसे चुनाव एक खुला मंच है। कोई भी उसमें भाग ले सकता है। किंतु उसके पूर्व प्रेस में जाकर तीरंदाजी करना उचित नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद और विवाद हितकर हैं, किंतु सर्व सम्मत फैसले के खिलाफ काम करना अहितकर है, खासकर किसी पार्टी के लिए। कुछ बाहर वाले तथा कांग्रेस समर्थक अखबार अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं।

माया : कहा जा रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रसन्न कांग्रेस है, क्योंकि वह देख रही है कि विलय विघटन में बदलता जा रहा है।

अजीत : यह प्रसन्नता बहुत जल्दी समाप्त हो जायेगी, क्योंकि बड़ी सामाजिक शक्तियां संयुक्त रूप से जनता के बीच उतर कर काम करने जा रही हैं। कांग्रेस जैसा बेवकूफी का काम अभी तक करती आ रही है, वैसी ही बेवकूफी करके इस मामले में भी खुश हो ले।

माया : नेताओं के स्तर पर नहीं तो क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर विलय संबंधी कठिनाइयां नहीं आयेंगी ?

अजीत : बात ठीक उलटी है। कुछ नेताओं में भले ही थोड़ा मतभेद हो, किंतु कार्यकर्ताओं में विलय को लेकर अत्यधिक उत्साह और प्रसन्नता है। हम लोग तीन-चार महीने से जो संयुक्त रैलियां, सभाएं आदि कर रहे थे, उससे एक प्रकार से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का विलय संपन्न हो चुका है। झगड़ा तो सिर्फ ऊपर का है।

माया : क्या इस विलय से असंतुष्ट हो आपका वोट बैंक लोकदल-ब, जनमोर्चा तथा कांग्रेस की ओर उन्मुख नहीं हो जायेगा ?

अजीत : ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं है। हमारा वोट बैंक पारंपरिक, समर्पित और कट्टर कांग्रेस विरोधी है। और जैसा कि सर्वविदित है, लोकदल-ब भी शीघ्र हमारे साथ आयेगा। ■

हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा है।''

एक अन्य नेता ने प्रश्न किया कि पूर्व जनता राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह अधिकार कतई नहीं है कि वह भविष्य संबंधी निर्णय ले। चाहे वह समिति के संबंध में हो या अंतरिम अध्यक्ष के बारे में। प्रश्न यह उठता है कि विवादों की भूल-भुलैया में उलझा यह मामला आगे क्या गुल खिलायेगा ? चन्द्रशेखर ने दोटूक शब्दों में इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने एक मई को पदत्याग करने का निश्चय किया है (देखें साक्षात्कार)। जानकार सूत्रों का यह भी दावा है कि विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को सरंजाम देने और पार्टी के सांगठनिक चुनाव कराने में अभी समय लगेगा।

इसके तीन संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। एक, यथास्थिति बरकरार रहे। अगले चुनाव होने तक अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात चन्द्रशेखर और अजीत सिंह अपने-अपने पदों पर बने रहें। यदि ऐसा हुआ, तो सवाल यह है कि जनता के उस असंतुष्ट खेमे पर क्या असर होगा जो पार्टी पर कब्जा करने के मंसूबे बांधे बैठा है ? इस खेमे के एक वरिष्ठ सांसद का दावा है कि यदि चन्द्रशेखर ने वायदे के अनुसार अध्यक्ष पद का त्याग नहीं किया, तो असंतुष्ट पुनः विद्रोह का झंडा उठाने को बाध्य हो जायेंगे।

पर्याप्त तैयारी के अभाव में यह संभावना भी है कि असंतुष्ट कुछ समय के लिए निराशा और अपमान का कड़वा घूंट पीकर पार्टी में यथास्थिति बनाये रखें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान वातावरण में विपक्षी एकता में विघटन की प्रक्रिया आरंभ करने की पहल से हर गुट हिचकिचायेगा, क्योंकि ऐसा करने से जनता में उसकी नीयत के प्रति संदेहों का बीजारोपण हो जाने की संभावना बनी रहेगी। अतः जब तक जन-सहानुभूति प्रांप्त करने की स्थिति न होगी, तब तक असंतुष्ट चुप्पी साध सकते हैं।

दूसरा परिदृश्य है : चंद्रशेखर पद त्याग कर दें और अंतरिम अध्यक्ष को बागडोर सौंप दी जाये। एक विश्वसनीय सूत्र का दावा है कि ऐसी स्थिति में मामला लोकदल-अ और अजीत सिंह के लिए पानी सिर से ऊपर गुजर जाने वाला हो जायेगा। नतीजतन अजीत सिंह न केवल लोकदल-अ को जनता पार्टी से बाहर ले जायेंगे, बल्कि जनता पार्टी के बहुतेरे सदस्यों को भी अपने साथ लेते जायेंगे।

तीसरी संभावना : चंद्रशेखर अध्यक्ष पद छोड़ दें, किंतु अंतरिम अध्यक्ष न बनाकर कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह को संपूर्ण कार्यभार सौंप दें। ऐसी हालत में कुछ असंतुष्टों का बाहर हो जाना तय लगता है। खासकर वे जो अजीत सिंह के व्यक्तित्व को देख रहे हैं, उनके वर्तमान और भावी प्रभाव और जनाधार से आंखें बंद किये हुए हैं।

क्या यह विलय अंततः विघटनकारी साबित होगा या व्यापक एकता की दिशा में उठाया गया एक पहला और निर्णायक कदम ? मजे की बात तो यह है कि पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक की पूर्व संध्या पर आयोजित बैठक में अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यह शगूफा छोड़ दिया था कि लोकदल-ब का एक गुट इस व्यापक आधार वाली जनता पार्टी में आने को आतुर है। सदस्यों के बारंबार पूछने पर भी अध्यक्ष महोदय यह बताने से मुकर गये कि वह गुट मुलायम सिंह यादव का था अथवा बहुगुणा का ?

वैसे यह ज्वलंत मामला भी दरपेश है कि यह सुलह है या युद्ध विराम ? यह मई तक चलेगा या उसके पूर्व ही तलवारें खिंच जायेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनता पार्टी लोकदल की संयुक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक पहली मई से पूर्व होने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ, तो पहली मई के पहले ही या तो संघर्ष का बिगुल बज जायेगा या सुलह का हाथ बढ़ जायेगा। हेगड़े द्वारा इस्तीफा देने की पेशकश से आसार अच्छे नजर नहीं आते।

—रंजना कक्कड़

अटल बिहारी वाजपेयी

भाजपा के बिना कांग्रेस का विकल्प नहीं

एक समय भारतीय जनमानस में भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृत, रास्वसंघ में दीक्षित होने के बावजूद कट्टरपंथी विचारों से असंपृक्त, सातवें दशक में प्रवेश करने वाले अविवाहित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनीतिज्ञों में हैं जो अपने सरस-सहज व्यवहार, हाजिरजवाबी, मौलिक चिंतन और बेजोड़ वक्ता के रूप में उतने ही प्रख्यात हैं, जितने जनसंघ और बाद में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में। भाजपा जैसी मध्यमवर्गीय पार्टी के शीर्ष के नेता होते हुए भी सीमित पार्टी हितों से वाजपेयी प्रायः मुक्त रहे हैं। यही कारण है कि प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और मान्यताओं को लेकर राजनीतिक सीमाबद्धता की जगह व्यापक राष्ट्रीय हितों और जनताजनार्दन के सरोकारों में उनकी गहरी निष्ठा रही है। विदेश मंत्री के रूप में भारत-सोवियत मैत्री को वोल्गा और गंगा के समान प्राचीन-पावन बता कर वाजपेयी ने अपने साथी-संघातियों को शायद कम, किंतु कम्युनिस्टों को अधिक चौंकाया था। आपातकाल की जेल यात्रा के दौरान लिखी कविताओं का उनका संकलन 'कैदी कविराज की कुंडलियां,' उन्हें एक दुनियादार, शातिर और जड़ राजनीतिज्ञ की जगह उनके स्वप्नद्रष्टा, संवेदनशील और सचेतन व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। जनता की नब्ज पहचानने वाले, लचीले, लोकप्रिय, लब्धप्रतिष्ठ नेता वाजपेयी को मात्र राज्यसभा सदस्य के रूप में हाशिये पर डालना पार्टी के लिए ही नहीं कदाचित विपक्ष के लिए भी एक क्षति है। 'माया' की उनसे वर्तमान ज्वलंत राजनीतिक समस्याओं और विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जो विस्तृत-बेबाक बातचीत हुई, उसके प्रमुख अंश :

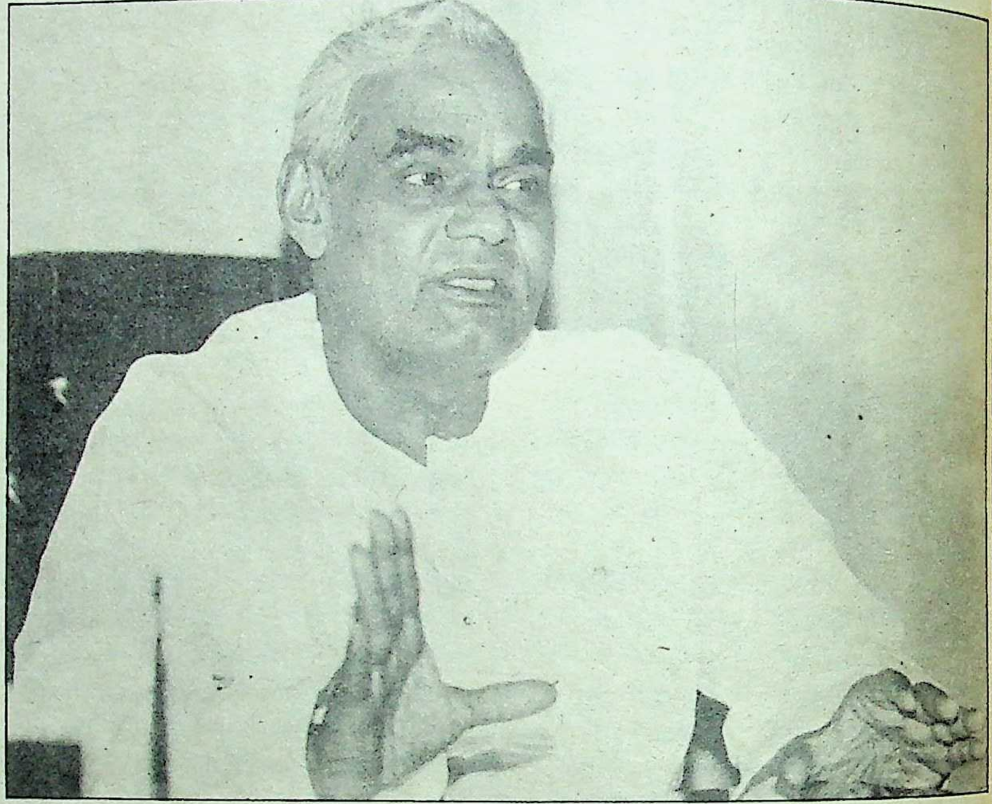

माया: *आप जैसा सक्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व आज सहसा निष्क्रिय हुआ जान पड़ता है। ऐसा क्यों?*

वाजपेयी: यह सही नहीं कि मैं निष्क्रिय हो गया हूं। राज्यसभा का पिछला अधिवेशन इस बात का प्रमाण है कि मैं अत्यधिक सक्रिय सदस्यों में था। इस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं—यह दायित्व पार्टी ने इस समय श्री अडवाणी को सौंपा है—इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी घोषणाएं श्री अडवाणी द्वारा होती हैं। मैं घोषणाएं करूं, ऐसी मुझसे आशा नही की जानी चाहिए।

माया: ***चर्चा तो यहां तक है कि आप राजनीतिक संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।***

वाजपेयी: ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं।

माया: ***क्या यह सही है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आपका तालमेल नहीं है और वैचारिक मतभेद हैं?***

वाजपेयी: क्या आपका तात्पर्य है कि मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं में नहीं हूं? (जोर से हंसते हुए...) इस आरोप में कोई सचाई नहीं है।

माया: *कहा जाता है कि आप द्वारा स्थापित-प्रतिपादित समाजवादी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष छवि बहुतों को रास नहीं आती। क्या यही आपके प्रति भाजपा की उपेक्षा और आरएसएस के रोष का प्रमुख कारण है?*

वाजपेयी: ये दोनों धारणाएं कि भाजपा मेरी उपेक्षा कर रही है और आरएसएस में मेरे प्रति रोष है, पूर्णतया निराधार हैं। गुजरात में हुए पार्टी अधिवेशन में गांधीवादी समाजवाद को लेकर लंबी और खुली बहस हुई थी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने यह फैसला कर लिया था कि हम गांधीवादी समाजवाद पर जोर नहीं देंगे। पर जब यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में गया, तो गरमागरम बहस के बाद तय हुआ कि जहां एकात्म मानववाद हमारा चितन होना चाहिए, वहीं आर्थिक क्षेत्र में हमें गांधीवादी समाजवाद का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसके प्रति पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अवश्य है कि कांग्रेस और कथित समाजवादियों ने समाजवाद की प्रतिष्ठा गिरा दी। भाजपा उस प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करना चाहती है।

माया: ***क्या पार्टी नेताओं में उस मुद्दे पर मतभेद नहीं हैं?***

वाजपेयी: कतई नहीं। यह सर्वसम्मत फैसला है। इस पर किसी के मतभेद का प्रश्न ही नहीं

उठता। सब इस फैसले से बंधे हुए हैं।

माया: ***भाजपा कितनी लोकतांत्रिक है?***

वाजपेयी: भाजपा कदाचित देश की सर्वाधिक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके निश्चित समय पर चुनाव होते हैं तथा कोई भी पदाधिकारी दो बार से अधिक अपने पद पर आसीन नहीं रहता है।

माया: ***किंतु कहा तो यह जाता है कि भाजपा मात्र दो नेताओं—वाजपेयी और अडवाणी की पार्टी रह गयी है तथा उसमें नये नेतृत्व पैदा करने की क्षमता नहीं रह गयी है।***

वाजपेयी: ऐसा बिलकुल नहीं है। पार्टी में नये नेता उभर रहे हैं। मिसाल के लिए प्रमोद महाजन का नाम लिया जा सकता है। प्रदेशों में नये लोग बागडोर संभाल रहे हैं। यह अवश्य है कि हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और नेतृत्व की मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। कोई छलांग लगाकर शिखर पर नहीं पहुंच सकता।

माया: ***क्या इसका अर्थ है कि अब तक कोई इस लंबे सफर को तय नहीं कर पाया?***

वाजपेयी: नहीं! अनेक लोग यह सफर पूरा कर चुके हैं। अडवाणीजी अपेक्षाकृत मुझसे कम आयु के हैं, राजमाता सिंधिया मुझसे अधिक उम्र की हैं। कृष्ण लाल शर्मा नये नेता के रूप में उभर रहे हैं। प्रदेशों में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है।

माया: ***पिछले ४० वर्षों से भाजपा कहीं अपने अकेले बलबूते पर सत्ता प्राप्त करने में सफल क्यों नहीं रही है?***

वाजपेयी: इसके अनेक कारण हैं। प्रमुख कारण है हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके विस्तार पर हमने अधिक बल दिया है। एक स्थान पर शक्ति केन्द्रित करके चुनाव जीतने की व्यूहरचना के लिए जितना महत्व देना चाहिए था, पार्टी ने उतना महत्व नहीं दिया है। हमारा उद्देश्य एक सशक्त प्रतिपक्ष प्रस्तुत करने का था। १९७७ में इस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो गया। दुर्भाग्य से हमारे शक्ति वाले अधिक क्षेत्र हिंदी प्रदेश में हैं। हिंदीभाषी क्षेत्र में क्षेत्रवाद को जगाकर सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। आंध्र, तमिलनाडु में केन्द्र विरोधी बातें करके अवश्य सत्ता प्राप्त की जा सकती है, हिंदी प्रदेश में नहीं। कारण हिंदीभाषी जनता केन्द्र को शक्तिशाली देखना चाहती है। दूसरा कारण है कि हमारा आधार जातिगत नहीं है। इसलिए एक स्थान पर शक्ति केन्द्रित करके चुनाव जीतने में हमें कठिनाई होती है। किंतु दिल्ली के स्थानीय प्रशासन की बागडोर हमारे हाथ में थी और हम उसमें पुनः विजयी होने की आशा करते हैं। मप्र में पार्टी ने ३० प्रतिशत के लगभग वोट प्राप्त किये हैं। यदि हम १० प्रतिशत वोट चुनाव के समय बहने वाली हवा के आधार पर प्राप्त कर लें, तो सत्तारूढ़ हो सकते हैं। विचारधारा प्रधान पार्टी के लिए [illegible] कठिनाई पैदा करता है। वैसे हरिजनों, आदिवासियों में जितना काम होना चाहिए, उसमें हम सफल नहीं हुए हैं। हमारी राष्ट्रवादी नीति के कारण मुस्लिम समुदाय से हमको दूर ले जाने की हमेशा कोशिश होती रहती है। हम विस्तार के साथ अपने कार्यों में गहराई देने के लिए प्रयत्नशील हैं। आशा है हम किसी स्थान पर बहुमत हासिल करके दिखायेंगे।

माया: ***वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा लगातार हाशिये पर जाती दिखायी दे रही है।***

वाजपेयी: मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाजपा का विधानमंडलों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है।

माया: ***क्या आप यह स्वीकारेंगे कि विपक्षी राजनीति में आपकी पार्टी अलग-थलग हो गयी है?***

वाजपेयी: ऐसी कोशिश की गयी थी, किंतु वह नाकाम रही। भाजपा के संबंध में वीपी सिंह को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ा है। जब संसद में ५९वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया, तो विपक्षी नेता राष्ट्रपति के पास. मार्च करके गये थे। उसमें कम्युनिस्टों को भाजपा सदस्यों के साथ चलने में कोई संकोच नहीं हुआ। 'हम भाजपा को चिमटे से भी नहीं छुयेंगे!' उन्हें अपनी यह हठवादिता तोड़नी पड़ी। इस प्रकार दलों का यह पुनर्विचार स्वागतयोग्य है। भाजपा के बिना केन्द्र में कांग्रेस का विकल्प तैयार नहीं हो सकता।

**वैसे हरिजनों,
आदिवासियों में जितना काम होना चाहिए,
उसमें हम सफल नहीं हुए हैं।
हमारी राष्ट्रवादी नीति के कारण मुस्लिम
समुदाय से हमको दूर ले
जाने की हमेशा कोशिश होती रहती
है। हम विस्तार के साथ
अपने कार्यों में गहराई देने के लिए
प्रयत्नशील हैं।**

माया: ***इस आरोप में कितनी सचाई है कि भाजपा आरएसएस का राजनीतिक मंच है?***

वाजपेयी: न भाजपा आरएसएस का राजनीतिक मंच है और न आरएसएस भाजपा का सांस्कृतिक मंच है। दोनों अलग-अलग संगठन हैं। दोनों के अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं। दोनों की नीतियों का निर्धारण और संचालन अलग-अलग केन्द्रों से होता है। भाजपा के द्वार सबके लिए खुले हैं।

माया: ***क्या भाजपा के इन्हीं विचारों और नीतियों के कारण आरएसएस कांग्रेस की ओर झुकने लगा है?***

वाजपेयी: मेरे लिए यह ताजी और रोचक खबर है कि आरएसएस कांग्रेस की ओर झुकने लगा है।

माया: ***बालासाहब देवरस ने साफ-साफ कहा है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस अच्छी है।***

वाजपेयी: उन्होंने यह नहीं कहा है। श्री देवरस ने कहा है कि कांग्रेस का इस समय कोई विकल्प नहीं है। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कांग्रेस का स्थान लेने वाला एक भी दल दिखायी नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस का विकल्प तैयार करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जब भारतीय जनता या मतदाता कांग्रेस को हटाना चाहेंगे, तो वे विकल्प का निर्माण स्वयं कर लेंगे। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से १९४४ से संबंधित हूं। यह ठीक है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में हिंदुओं के दिमाग में प्रयत्नपूर्वक यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की गयी थी कि इंदिराजी ही हिंदुओं की हित-रक्षक हैं। इसलिए हिंदुओं को सिखों के विरुद्ध इंदिरा गांधी का साथ देना चाहिए।

माया: ***बात केवल सिखों की नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले चुनावों के दौरान आरएसएस ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी का साथ दिया था।***

वाजपेयी: हमने स्वयं उनका जमकर विरोध किया था। इस प्रयत्न में हमारी पराजय हो गयी। लेकिन जम्मू के हिंदुओं में इंदिरा गांधी यह भ्रम पैदा करने में सफल हो गयी थीं कि वह हिंदुओं की रक्षक हैं।

माया: ***किंतु आरएसएस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम इस कार्य में उनके साथ सहयोग किया था।***

वाजपेयी: हो सकता है कि आरएसएस के समर्थक उस हवा में बह गये हों, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में फिर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आने में सफल हुए हैं। पिछले चुनावों में हमने दो सीटें जीतीं और अनेक में बहुत कम वोटों से हारे। इंदिरा गांधी के हिंदूवादी होने का भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिका। राजीव गांधी के लिए यह भ्रम अगले चुनावों में काम नहीं आयेगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस

कोई भी खतरनाक खेल खेल सकती है।

माया : ***कांग्रेस ने अगले चुनाव में भी यदि अपना यह हिंदू पत्ता खेला, तो क्या सफल होगी?***

वाजपेयी : एक पत्ता एक बार ही फेंका जाता है। बार-बार वही पत्ता फेंक कर बाजी नहीं जीती जाती।

माया : ***यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आरएसएस के अपने प्रति व्याप्त असंतोष के कारण भाजपा अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो गयी है और इसके तहत उसने कड़ा रवैया और जुझारू तेवर अपनाया है।***

वाजपेयी : पार्टी जुझारू हो, यह हमारा प्रयत्न पहले से रहा है। आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर हम जुझारू तेवर अपनायें, यह नया जनसमर्थन हासिल करने और पुराने जनसमर्थन को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। किंतु इस जुझारूपन का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि भाजपा की लोकप्रियता घटने लगी थी और इसलिए हमने यह तौर-तरीका अपनाया।

माया : ***क्या यह सच है कि वर्तमान कड़ा रवैया और जुझारू तेवर आपको कम पसंद है? आम धारणा यह है कि पार्टी के हाल के इन निर्णयों से स्वयं आपका मतभेद रहा है।***

वाजपेयी : अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ, जिसमें मेरी राय भिन्न हो और यदि कभी राय भिन्न होगी, तो मैं उसे ईमानदारी के साथ पार्टी के सामने रखूंगा। पार्टी में स्वतंत्र चिंतन होता है। उन्मुक्त विचार-विमर्श होता है। लोकतांत्रिक पार्टी में तो मतभेद होते ही रहते हैं। लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए।

माया : ***विपक्ष की प्रमुख पार्टी के नाते विपक्षी एकता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने में भाजपा क्यों उदासीन और विफल है?***

वाजपेयी : अगर पार्टियों की एकता से अभिप्राय सब पार्टियों के विलय और एक पार्टी के निर्माण से है, तो उससे हमारा मतभेद है। कांग्रेस को हराने के लिए प्रतिपक्ष निकट आये, यह मतदाता चाहते हैं। किंतु मतदाता यह भी चाहते हैं कि १९७७ के बाद १९७९ में जो कुछ हुआ, वह फिर से दोहराया न जाये। इसलिए एकता पर बल देने के बजाय हम विश्वसनीयता पर बल देते हैं। हरियाणा में लोकदल-ब के साथ भाजपा ने मिलकर संघर्ष किया, मिलकर चुनाव लड़ा और आज हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। हरियाणा जैसा ढांचा और भी प्रदेशों में बनाया जा सकता है। जो दल विलय के लिए तैयार हैं, वे अपने को विलीन कर दें। लेकिन जो दल इसके लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें राजीव सरकार को हटाने के लिए अपने को तल्लीन कर देना चाहिए। विलय के प्रयत्नों में मतभेद हों, उन मतभेदों की चर्चा समाचारपत्रों में हो, फिर इससे वातावरण बिगड़े, लोगों को यह कहने का मौका मिले कि वे अभी मिले नहीं हैं, लेकिन झगड़ा शुरू कर दिया। हम इस अप्रिय स्थिति को टालना चाहते हैं। जनता पार्टी में शामिल घटक और उनके महत्वाकांक्षी नेता एक साथ चलने में विफल रहे। इससे जनता पार्टी टूट गयी।

माया : ***विपक्षी एकता की संभावना आज आपको कैसी दिखायी दे रही है?***

वाजपेयी : विपक्षी दल और नेता मुद्दों को भूलकर और संघर्षों को छोड़कर यदि शिखर सम्मेलनों और रात्रिभोजों के आधार पर नेताओं का समीकरण बिठाने के खेल में फंस गये, तो इसमें कठिनाई पैदा हो सकती है। मेरी राय में कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग को छोड़कर जनमोर्चा सहित तमाम विपक्षी दलों की एक समन्वय समिति बननी चाहिए। अभी तक तो देश की एकता और अखंडता खतरे में थी, अब ५९वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। इस मुद्दे को लेकर प्रचंड आंदोलन विपक्ष चला सकता है। इससे सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा और पार्टियां निकट आयेंगी, लोगों में भी उनके प्रति भरोसा पैदा होगा।

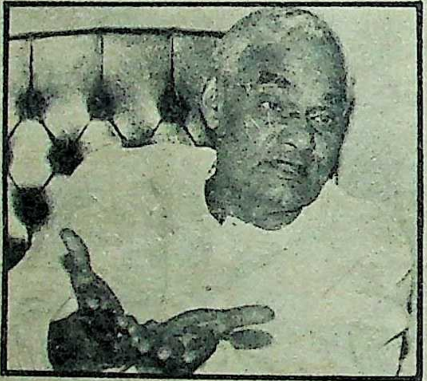

मेरी राय में कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग को छोड़कर जनमोर्चा सहित तमाम विपक्षी दलों की एक समन्वय समिति बननी चाहिए। अभी तक तो देश की एकता और अखंडता खतरे में थी, अब ५९वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है।

माया : ***क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और उनके द्वारा राष्ट्रीय पार्टियों को अपदस्थ करने का सिलसिला देश को किस दिशा और दशा में ले जायेगा?***

वाजपेयी : क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के लिए कांग्रेस की अत्यधिक केन्द्रीयकृत नीति जिम्मेदार है। जब मुख्यमंत्री सूबेदार मात्र रह गये हैं, विधायकों से मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार छीन लिया गया है और नयी दिल्ली के इशारे पर राजकाज चलने लगा है, तो लोगों में उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। किंतु क्षेत्रीय दलों का उदय राष्ट्रीय दलों के लिए घातक नहीं है। वैसे यह कोई स्थायी प्रवृत्ति भी नहीं है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने और राज्यों के फैसले राज्य स्तर पर होने से क्षेत्रीय दलों के उदय का मार्ग अवरुद्ध होगा। बहरहाल दल भले ही क्षेत्रीय हों, किंतु उनका लक्ष्य राष्ट्रीय होना चाहिए। केन्द्र में जो भी सरकार हो, उसमें क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजीव गांधी ने भी अन्नाद्रमुक सरकार का समर्थन किया था। भविष्य में हम ऐसी सरकार की कल्पना कर सकते हैं, जिनमें अन्नाद्रमुक, असम गण परिषद आदि क्षेत्रीय दल शामिल हों।

माया : ***क्या आपको लगता है कि विपक्ष के सामने अवसर पुनः दरपेश है? भारतीय जनता पिछले अनुभवों के आधार पर विपक्ष पर कैसे विश्वास करेगी?***

वाजपेयी : देश परिवर्तन के लिए तैयार है। विपक्ष को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जहां तक जनता का प्रश्न है, उसे अपना मन बनाना होगा कि सचमुच उसे कांग्रेस को हटाना चाहिए या नहीं।

माया : ***तो क्या आप नकारात्मक मत से सत्ता में आना चाहते हैं?***

वाजपेयी : लोकतंत्र में नकारात्मक मतों से ही सत्ता-परिवर्तन होता है। १९७७ में यही हुआ। इमरजेंसी की ज्यादतियों के खिलाफ जनता ने वोट दिया। १९८० में जनता पार्टी की फूट की वजह से उसने कांग्रेस को वोट दिया। १९८४ में लोग देश को विभाजित करना चाहते थे। उसके विरुद्ध लोगों ने राजीव गांधी को समर्थन दिया। अब राजीव गांधी के भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता, बढती महंगाई, बेकारी पर क्रुद्ध जनमानस अपना रोष प्रकट करेगा। किंतु विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने एक ठोस, समयबद्ध कार्यक्रम रखे। साथ ही लोगों को विश्वास दिलाये कि वह एक साफ सुथरी और कारगर सरकार बनाने में सक्षम है जो बुनियादी समस्याएं हल करेगी। यदि वह यह प्रयत्न कर सकेगा, तो जनता का समर्थन उसे प्राप्त होगा।

माया : ***देवीलाल ने आपको जो पत्र लिखा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?***

वाजपेयी : देवीलाल के पत्र में एक नयी पार्टी बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कम्युनिस्टों को छोड़कर अन्य दलों और नेताओं की एक समिति बननी चाहिए। यह समिति राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करे और लोगों को नयी दिशा दे। हमारी पार्टी उनके इस दृष्टिकोण से सहमत है।

माया : ***क्या वीपी सिंह के अलावा कोई अन्य नेता विपक्ष को नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता?***

कभी-कभी मैं सोचता हूं कि सरकार चाहती है कि पंजाब और अन्य स्थानों पर थोड़ी-बहुत गड़बड़ी चलती रहे, जिससे राजीव सरकार को अपनी तमाम विफलताओं पर परदा डालने का मौका मिले। चुनाव का समय आये, तो वह देश खतरे में है, यह नारा लगाकर जनसमर्थन प्राप्त कर लें।

वाजपेयी: मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता।

माया: *देवीलाल के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि नेता पार्टी बनाता है, पार्टी नेता नहीं बनाती?*

वाजपेयी: मुझे तो मेरी पार्टी ने नेता बनाया। यह पार्टी के स्वरूप, गठन और चरित्र पर निर्भर करता है कि वह नेता बनाती है या नेता उसे बनाता है। आंध्र में रामाराव ने अपने दम पर पार्टी खड़ी कर ली। लेकिन ऐसा प्रयोग हर जगह नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। लोकतंत्र की सफ़लता के लिए पार्टी प्रणाली को मजबूत करना अत्यावश्यक है।

माया: *वर्तमान सरकार की विदेश नीति कैसी है मसलन श्रीलंका, अफगानिस्तान के मामलों में?*

वाजपेयी: इस सरकार की अफगानिस्तान के संबंध मे कोई नीति नहीं है। उसकी खोज की जा रही है और वह भी टेलीफोन द्वारा। मैं नहीं समझता कि अफगान समस्या को हल करने में भारत सरकार कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की स्थिति में है। यदि हम अफगानिस्तान मे सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के प्रारंभ में ही दोस्ताने, किंतु दृढ़ स्वर में विरोध करते, तो यह संकट की स्थिति न पैदा होती। अब हालत यह है कि भारतीय सेना श्रीलंका में फंस गयी है, कब वापस आयेगी कहना मुश्किल है। श्रीलंका समझौता बुनियादी तौर पर ठीक था, किंतु उस पर अमल गलत ढंग से किया गया। हमने प्रारंभ से साफ और दोटूक नीति नहीं अपनायी। हम आंतकवादियों को आश्रय भी देते रहे, उनकी मदद भी करते रहे। श्रीलंका सरकार पर हमें जितना दबाव डालना चाहिए था, उतना दबाव हमने नहीं डाला। श्रीलंका के मामले में हमने नयी दिल्ली में अलग-अलग संकेत दिये। प्रधानमंत्री के सलाहकार बदलते रहे हैं, सलाहकार बदलने के साथ-साथ प्रधानमंत्री की श्रीलंका की नीति भी बदलती रही है। लेकिन जब समझौता हुआ, तब भारत को मध्यस्थता का काम करना चाहिए था। समझौते की गारंटी का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। अब यह स्थिति है कि भारतीय सेना एलटीटीई को दबा और कुचल रही है। यदि भारतीय सेना वापस आ गयी और श्रीलंका की सेना [illegible] एलटीटीई के अभाव में तमिलों की रक्षा कौन करेगा। एलटीटीई पर भी दबाव डालकर उसे लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाने और श्रीलंका की राष्ट्रीय मुक्तधारा में शामिल होने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सरकार श्रीलंका सेना और एलटीटीई, इन दोनों पर ही दबाव डालने में विफल रही है।

माया: *पाकिस्तान जहां पंजाब के आतंकवादियों को सहायता दे रहा है, वहीं भारत सरकार आधिकारिक रूप से उस पर विरोध भी नहीं जता रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?*

वाजपेयी: यही तो मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूं। पहले वह मामला जोरशोर से उठाया जाता था, बाद में सरकार ने इसे उठाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कहा था कि यदि भारत सिंध में हस्तक्षेप बंद कर दे, तो पाकिस्तान भी पंजाब में हस्तक्षेप बंद करने को तैयार है। मुझे ज्ञात नहीं कि भारत सिंध में हस्तक्षेप कर रहा है। यदि कर रहा है, तो गलत है।

माया: *जब आप विदेश मंत्री थे, तब इस मुद्दे पर भारत-पाक संबंध कैसे थे?*

वाजपेयी: तब स्थिति संतोषजनक थी। न हम उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते थे, न उन्हें ऐसा करने का मौका देते थे। कुछ भी हो, यदि पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, तो यह मामला गंभीरतापूर्वक पाकिस्तान से उठाया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल ले जाना चाहिए। हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी दखलअंदाजी के खिलाफ सरकार एक श्वेतपत्र प्रकाशित करे। यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके अलावा पाकिस्तानी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से कौन हमें रोक सकता है? यदि पाकिस्तान हथियार भेजता है, तो सवाल यह है कि उन हथियारों को हम आने कैसे देते हैं? अब जब एक ही रात में आतंकवादियों ने पंजाब में ३४ लोगों की हत्या कर दी, तो सरकार यह ऐलान करती है कि वह सीमा को सील करने जा रही है। दो साल पूर्व राज्यसभा में अनुच्छेद २४६ के अंतर्गत प्रस्ताव आया था। विरोधी दलों में एकमात्र भाजपा ने ही उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उसके तहत सीमा पर एक सुरक्षा पट्टी बननी थी। वह पट्टी आज तक नहीं बनी। वह बनेगी भी, इसका मुझे भरोसा नहीं।

माया: *ऐसा आप क्यों सोचते हैं?*

वाजपेयी: कारण सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि सरकार चाहती है कि पंजाब और अन्य स्थानों पर थोड़ी-बहुत गड़बड़ी चलती रहे, जिसमे राजीव सरकार को अपनी तमाम विफलताओं पर परदा डालने का मौका मिले। चुनाव का समय आये, तो वह देश खतरे में है, यह नारा लगाकर जनसमर्थन प्राप्त कर लें।

माया: *आपके विदेश मंत्री के कार्यकाल में इस्रायल भारत से संपर्क बढ़ाने को इच्छुक था। इसीलिए मोशे दयान भारत आये थे। आप पीछे क्यों हट गये थे?*

वाजपेयी: इस्रायल सदा में भारत के साथ मैत्री संबंध कायम करना चाहता था। जब नेहरूजी प्रधानमंत्री थे, तो इस्रायली नेताओं से उनका निकट का संपर्क था। इंदिरा गांधी के जमाने में भी परदे के पीछे यह संपर्क कायम था। इस्रायल की नीतियों से हमारा मतभेद है, किंतु इस्रायल न भारत के खिलाफ अभी तक कोई काम नहीं किया है।

माया: *किंतु तब आपने हाथ क्यों खींच लिया था?*

वाजपेयी: हमने कहा कि दोस्ती के लिए पहले हमारा संबंध सामान्य हो। पहले आप अरबों के उस इलाके को खाली कीजिए, जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। पश्चिम एशिया का स्थायी समाधान ढूंढ़ने का प्रयास कीजिए। मोशे दयान अपनी इच्छा से भारत आये थे और बातचीत के दौरान भारतीय दृष्टिकोण को उन्होंने समझा था। खेद का विषय है कि वर्तमान सरकार की इस बारे में कोई नीति ही नहीं है।

माया: *अलगाववादी शक्तियां-मसलन पंजाब, गोरखालैंड क्यों जोर पकड़ती जा रही हैं?*

वाजपेयी: पंजाब समस्या कांग्रेस ने अपनी संकुचित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पैदा की है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार को मुसीबत में डालने के लिए कांग्रेस ने गोरखालैंड की समस्या को हवा दी है। अलगाववाद को जब सत्ता प्राप्त करने या उसे बनाये रखने का औजार बनाया जाता है, तब अलगाववाद देश के लिए खतरा होता है। हमारी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक नीतियां सही होतीं और राष्ट्रीयता की भावना का समुचित प्रचार किया जाता, तो ऐसी चिंताजनक स्थिति न पैदा होती। जब हमने 'इंडिया' की जगह 'इंदिरा' को अधिक महत्व देना शुरू किया, तो फिर राष्ट्रीय निष्ठा का दुर्बल होना स्वाभाविक है।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

भाजपा का आगरा अधिवेशन

पुरानी पहचान बनाने की कोशिश

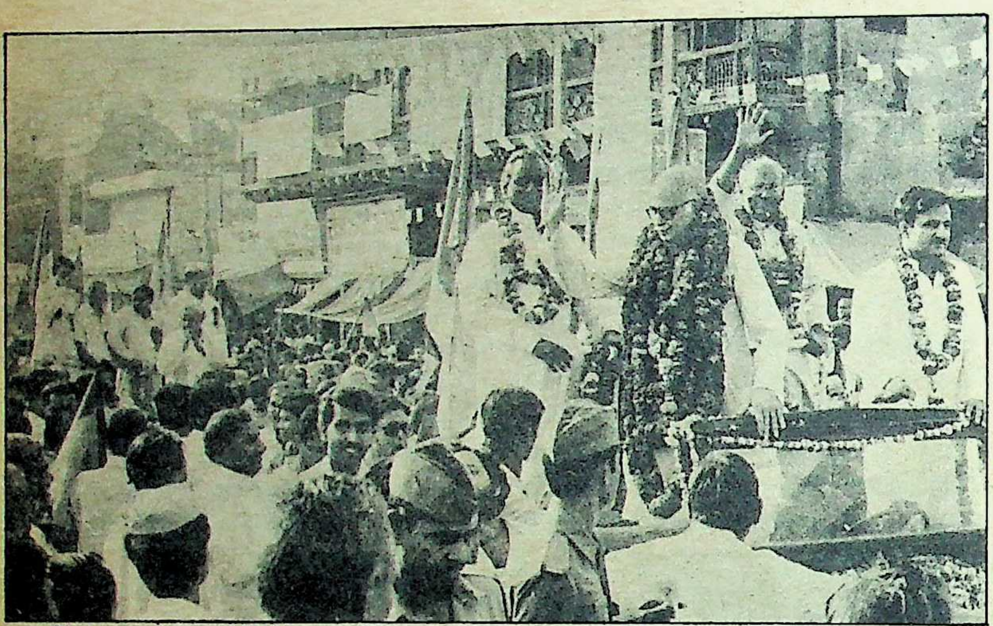

चुनावों पर नजर : भाजपा की शोभायात्रा में अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और अटलजी

भारतीय जनता पार्टी के आगरा महाधिवेशन में काफी सोच-विचार के बाद 'शिखर की राजनीति' के बजाय 'धरती की राजनीति' करने का फैसला किया गया है। इसके तहत भाजपा ने आगामी लोकसभा के चुनाव को 'अपने नाम, निशान और अपनी ताकत' के बल पर लड़ने के लिए लचीली रणनीति अपनाने का फैसला किया है, जिसके अन्तर्गत जरूरत पड़ने पर कम्युनिस्टों और मुस्लिम लीग को छोड़कर देश के हित में अन्य दलों के सात चुनावी गठजोड़ अथवा समझौता' किया जा सकता है। यही वजह है कि भाजपा की निगाह में हरियाणा का गठबधन एक 'महान आदर्श' है, जहां वह लोकदल-ब के साथ 'सत्ता सुख' भोग रही है।

चुनाव की तैयारी: ६ और ७ अप्रैल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और ८ अप्रैल से १० अप्रैल तक चले महाधिवेशन में जो भी विचार-विमर्श हुआ तथा जो भी निर्णय किये गये, वे सब-के-सब आगामी चुनावों को दृष्टि में रखकर लिये गये। चाहे वह पंजाब की ज्वलंत समस्या हो अथवा हरिजनों को न्याय दिलाने की बात हो, या फिर आन्तरिक लोकतंत्र कायम न रखनेवाली राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने की मांग के साथ ही किसानों को ऋणयुक्त करने का सवाल हो-हर मुद्दे पर जो भी फैसले किये गये, वे सभी चुनावी रणनीति के अंगमात्र थे। इसी के तहत भाजपा ने हिन्दीभाषी क्षेत्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के तेजी से उभर कर सामने आने के सवाल पर कोई साफ राय नहीं बनायी। भाजपा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली के अपने वर्चस्व को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। साथ ही उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अपना पुराना प्रभाव वापस लानां चाहती है। फिलहाल वीपी सिंह के बारे में उसने सद्भावना और सावधानी की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। भाजपा इस मामले में हरियाणा के अपने 'बड़े भाई देवीलाल' को नाराज नहीं करना चाहती है, जिन्होंने अपनी तरफ से वीपी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान पिछले दिनों किया था।

यद्यपि कार्यकारिणी की बैठक में संयुक्त विपक्ष के एकमात्र नेता के रूप में राजा माण्डा को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन इस सवाल पर काफी तीखे मतभेद भी उभरकर सामने आये। एक तरफ राजस्थान के भाजपा स्तंभ भैरो सिंह शेखावत और गुंजरात प्रान्त के श्री के देसाई, राजा माण्डा के प्रबल समर्थक थे, तो दूसरी तरफ पार्टी उपाध्यक्ष सिकंदर बख्त उनके कट्टर विरोधी।

वामपंथियों पर गुस्सा: महाधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से आये लगभग दस हजार प्रतिनिधियों में मार्क्सवादियों के प्रति चिढ़ का वही रुख देखा गया, जो साम्यवादियों ने कभी भाजपा के प्रति अपनाकर उसे मध्यममार्गी विपक्ष से अलग-थलग कर दिया था। इसी के साथ कार्यकारिणी और महाधिवेशन में शामिल सदस्य अपने अध्यक्ष आडवाणी के इस मत से भी सहमत थे, "इतिहास की एक दुर्घटना इस महान देश की बागडोर बौनों की एक ऐसी मण्डली के हाथों में पहुचा दी है, जो न केवल अयोग्य और भ्रष्ट है, अपितु देश और उसकी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तानाशाही के सीकचों में कैद करने पर तुली हुई है।" शायद इसलिए महाधिवेशन ने एक स्वर से फैसला लिया "हम बौनों की उस मण्डली के मुखिया राजीव गांधी को हटाने के मध्यवर्गी संयुक्त विपक्ष के हर संघर्ष में भागीदार रहेंगे।"

महाधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में यह भाव साफ नजर आ रहा था कि भाजपा को हर हालत में १९६७ की भारतीय जनसंघ की अस्मिता को वापस लाना चाहिए और कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किये जाने चाहिए। उन्हें १९७७ में जनता पार्टी में जनसंघ को विलीन कर देने का दर्द आज भी साल रहा है।

पंजाब समस्या के संदर्भ में भाजपा ने इस महाधिवेशन में एक ओर पाकिस्तान के खिलाफ़ कड़े रुख को अपनाते हुए उसे सबक सिखाने के लिए अणुबम बनाने की जोरदार मांग उठायी, तो दूसरी ओर हिन्दू-सिख एकता की दुहाई देकर बालठाकरे की शिवसेना की सिख विरोधी नीतियों का सक्रिय विरोध करने का ऐलान भी किया। इस तरह आगरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा ने अपने से अलग होती जा रही हिन्दू भावना को पकड़ने की जहा एक बार फिर कोशिश की है, वहीं अपने वोट आधार को बढ़ाने के लिए हरिजनों को अधिक सुविधा देने तथा भूमि सुधार योजनाएं लागू करने का राग भी अलापा है।

जो भी हो, भाजपा का आगरा अधिवेशन अपनी पुरानी अस्मिता को वापस लाने, वामपंथियों की पेशबंदियों से अलग होने के अहसास को तोड़ने और मध्यमार्गी राजनीतिक जमातों में पैनापन लाने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम साबित हो सकता है। वैसे अगर विश्लेषण किया जाये, तो भाजपा की आज की चुनावी स्थिति कमोबेश १९५७ की भारतीय जनसंघ की स्थिति जैसी ही हो रही है। तब जनसंघ के उत्तर प्रदेश विधानसभा में १७ विधायक थे, जबकि आज भाजपा के १६ हैं। उस समय राज्य से लोकसभा में जनसंघ के दो सदस्य थे, लेकिन आज एक भी सदस्य न होते हुए भी इसे अजीब विडम्बना ही कहा जायेगा कि पूरी लोकसभा में उसके केवल दो सदस्य ही हैं। अगले चुनावों में उसे १९६७ वाले जनसंघ के रिकार्ड को पाने के लिए जोरदार कोशिश करनी पड़ेगी। तब लोकसभा में सबसे अधिक कुल ३५ जनसंघी सदस्यों में से १२ उत्तर प्रदेश से चुने गये थे और राज्य विधानसभा में उसके सर्वाधिक ९८ विधायक थे।

देखना है कि क्या आज की भाजपा तब के जनसंघी कार्यकर्ताओं को अपने नजदीक लाकर १९६७ के जनसंघ जैसा चुनावी रिकार्ड दोहरा पायेगी? फिर से भाजपा के अध्यक्ष चुने गये लालकृष्ण आडवाणी की तो मान्यता है, "इस देश में इंका का विकल्प केवल भाजपा ही है। नीति के नाते, कार्यक्रम के नाते, अथवा राजनीतिक संस्कृति के नाते वही एकमात्र विकल्प है।"

—आगरा से अशोक रजनीकर

छाया: कला कु

मोटर-कार का युग आ ही रहा था और घोड़ा-बग्गी का ज़माना समाप्त हो रहा था, शरबत रूह अफ़्ज़ा उस समय भी मौजूद था.

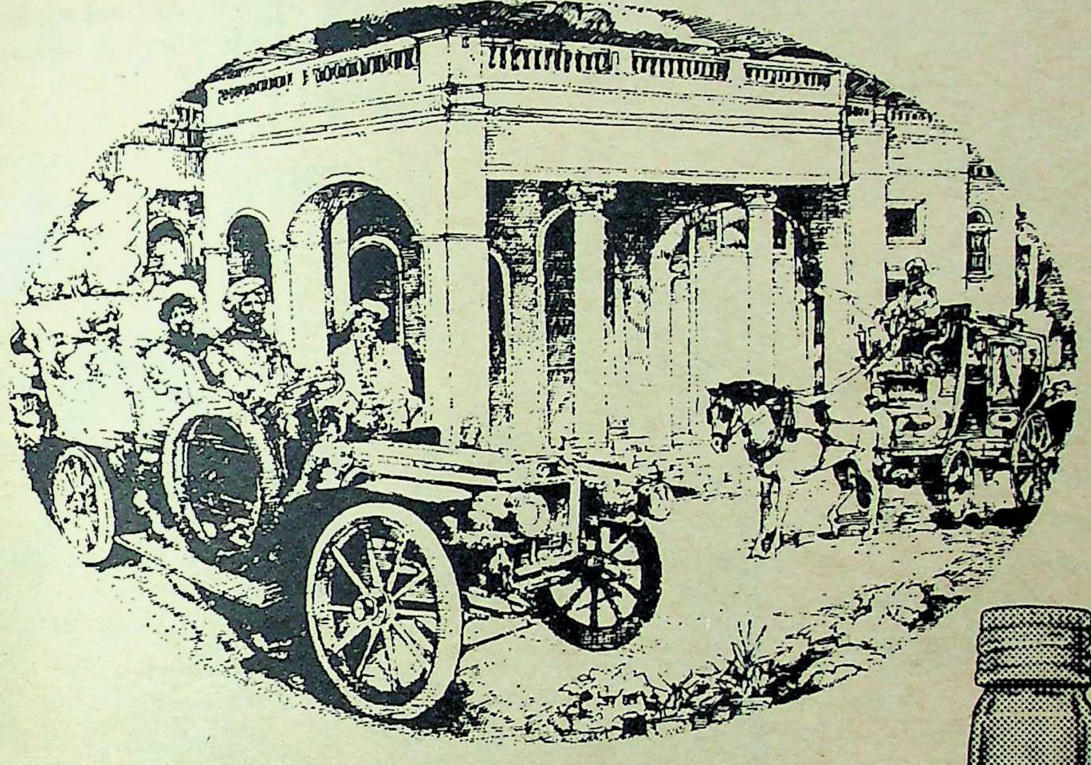

८० वर्षों से अधिक समय से सब का मनपसन्द शरबत

रूह अफ़्ज़ा सदा से गर्मी के मौसम की तपन, थकान और प्यास को दूर करके शरीर में चुस्ती और तरावट पैदा करता है। इस में सन्तरे और अन्नानास के रस के साथ गाजर, तरबूज़, लौकी और पालक, आदि का एक्सट्रैक्ट भी शामिल है जिस से आपको प्राकृतिक विटामिनों और जीवनदायक तत्त्वों का भण्डार प्राप्त होता है।

अब देश के गौरवशाली वैज्ञानिकों ने भी विस्तृत अनुसंधान के पश्चात शरबत रूह अफ़्ज़ा के सुप्रसिद्ध स्वास्थ्यदायक लाभों को अपनी रिसर्च से ठीक सिद्ध कर दिया है।

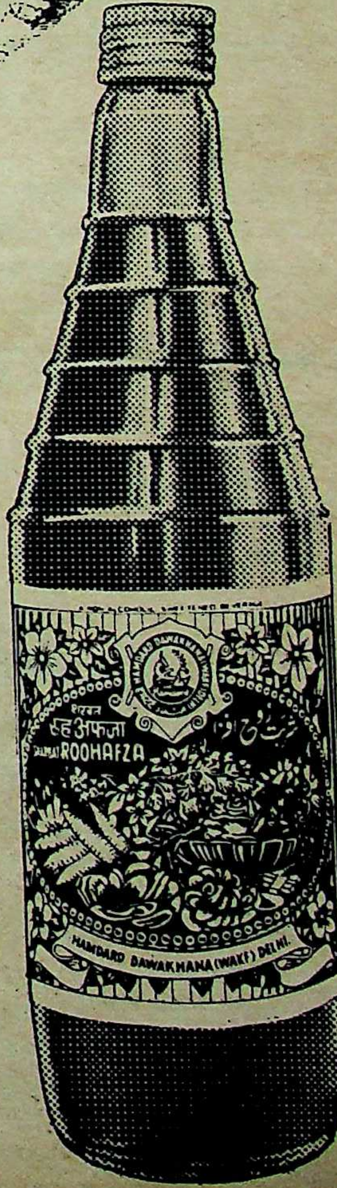
शरबत
रूहअफ़्ज़ा
SHARBAT ROOHAFZA
HAMDARD DAWAKHANA (WAKF) DELHI

हमदर्द

शरबत
रूह अफ़्ज़ा

जड़ी-बूटियों, जीवनदायक तत्त्वों और प्राकृतिक विटामिनों से तैयार अनोखा मिश्रण

HTA 5004 B

आपके पूरे परिवार के शारीरिक आराम की बात तो Kurl-on® ही जाने

क्या आप नहीं सोचते कि आपका परिवार सर्वश्रेष्ठ क्र हकदार हैं? कर्ल-आन लीजिए। पूर्ण आराम पाइये।

फोम का "मुलायम" गद्दा बदन को न तो सहारा देता है, न ही नमी सोखता है, नतीजा रातों की नींद हराम।

रूई के गद्दे, वैसे मुलायम, पर धीरे-धीरे लटके-लुढ़के, सख्त, बेढंगे और संभालने मुश्किल हो जाते हैं।

इस सूरत में आपके परिवार को जरूरत है खूबसूरंत कर्ल-आन की।
रबड़ चढ़े कॉयर पर मुलायम गद्दे की परत।
इतना मुलायम कि आपकी सांस के साथ दबे-फूले।

सहारा भी तो।

पूर्ण शारीरिक आराम का एहसास।
कर्ल-आन के विभिन्न गद्दों की बहार।
गिलाफ चढ़ी टेपस्ट्रियां भी तो कमाल की हैं।

आराम सहारे और शान के लिए
Kurl-on®
हां जनाब! हर तरह लाजवाब

कर्नाटक कन्ज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
मार्केटिंग डिविजन
इंडस्ट्री हाऊस, 45, फेयर फिल्ड रोड
बेंगलोर: 560 001. फोन: 72710, 70769

Area Sales Offices: Bangalore Ph: 76746, 220314 & 224676; Cochin Ph: 366744; Madras Ph: 831710; Hyderabad Ph: 234560; Calcutta Ph: 282089; Bombay Ph: 5113220; Ahmedabad Ph: 462601; Delhi Ph: 772019 & 732133; Guwahati Ph: 23612 (PP); Rourkela Ph: 2535 (PP); Hosur Ph: 6992.

Offices also at Patna, Bhubaneswar, Faridabad, Ghaziabad, Margoa and Bhopal.

MASS/KURL-ON/88

सत्ता के लिए जंग शुरू

तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण भागों में जहां स्व० रामचंद्रन की मतदाताओं पर जबरदस्त पकड़ थी, फिल्मी पोस्टरों में रामचंद्रन और जयललिता को साथ-साथ दिखाया जा रहा है। नयी फिल्मों की जगह स्व० रामचंद्रन की वे पुरानी फिल्में दिखायी जा रही हैं, जिनमें उन्होंने जयललिता के साथ काम किया था। इन क्षेत्रों की दीवारें 'पुराची थालसिवार और पुराची थलाइवी' (क्रांतिकारी पुरुष व क्रांतिकारी स्त्री) फिल्मों के रंगीन पोस्टरों से अट गयी हैं। इनमें अधिकतर पोस्टर वे हैं, जिनमें स्व० रामचंद्रन और जयललिता रूमानी मुद्रा में हैं। इस प्रकार अगस्त-सितंबर में संभावित विधानसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु में फिल्मों और फिल्मी पोस्टरों के जरिए अभी से सत्ता की जंग शुरू हो गयी है।

सत्ता के दावेदार : स्व० रामचंद्रन के बाद तमिलनाडु की सत्ता के दावेदारों में जयललिता के साथ-साथ जीके मूपनार, शिवाजी गणेशन और के करुणानिधि के नाम चर्चा में हैं, तो वीरप्पन-जानकी गुट भी चुप नहीं बैठा है। मूपनार के साथ-साथ चिदंबरम का भी यही विचार है कि तमिलनाडु में कांग्रेस-इ के लिए सत्ता तक पहुंचने का मार्ग वर्तमान परिस्थितियों में आसान हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली और मद्रास के बीच कांग्रेस-इ नेताओं की आवाजाही बढ़ गयी है। कांग्रेस हाईकमान ने जहां मद्रास में कांग्रेस-इ का अखिल भारतीय अधिवेशन करने की घोषणा की है, वहीं प्रदेश कांग्रेस-इ ने १४ अप्रैल तक एक हजार चुनावी सभाएं भी आयोजित कर डाली हैं। (१४ अप्रैल, नये तमिल वर्ष का पहला दिन था।)

चर्चा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल पीसी अलेक्जेण्डर भी कांग्रेस-इ के लिए अनुकूल माहौल बनाने में जुटे हैं। उन्होंने जिस तेजी से स्व० रामचंद्रन के समय से अटकी ३५०० फाइलों को निपटाया है, उसे इसी बात का संकेत माना जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस-इ ने बिना किसी से गठबंधन किये तमिलनाडु की सत्ता हथियाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वहीं दूसरी ओर जानकी रामचंद्रन, करुणानिधि, शिवाजी गणेशन और वीरप्पन भी अपने-अपने ढंग से सक्रिय हैं।

कांग्रेस का पलड़ा दो मायनों में भारी बताया जा रहा है—एक तो धन के मामले में, उसके पास असीम स्रोत हैं, दूसरे तमिलनाडु में प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष मूपनार के रूप में उसके पास एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पलानियांडी के समय प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी में आपसी गुटबाजी से जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसे मूपनार ने कुछ असंतुष्टों को कमेटी में लेकर दूर कर दिया है। जयललिता के चुनावी प्रचार का मुकाबला करने के लिए कहा जाता है कि दूरदर्शन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। एक स्थानीय पत्रिका के अनुसार, "ऐसा लगता है कि दूरदर्शन मूपनार की सभा कवरेज करते समय अपना कैमरा मूपनार पर ही स्थिर कर देता है।"

जयललिता

जानकी रामचंद्रन

ऐसी भी अफवाहें हैं कि कांग्रेस-इ अपने चुनाव प्रचार में दक्षिण भारत के लोकप्रिय फिल्मी सितारों को लगाने के लिए प्रयत्नशील है। इस संबंध में श्रीदेवी, रजनीकांत व कमल हासन के नाम बड़े जोरों से लिये जा रहे हैं। जयललिता गुट ने कांग्रेस-इ के इस तेवर को देखकर जयललिता को भावी मुख्यमंत्री कहना शुरू कर दिया है, तो स्वयं जयललिता यह घोषणा कर रही हैं कि यदि आवश्यकता महसूस हुई, तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जयललिता की इन घोषणाओं से पनरुटी रामचंद्रन और नेदुनचेझियन भी बहुत खुश नहीं हैं। ये दोनों स्व० रामचंद्रन की सरकार में मंत्री थे। तमिल पत्र-पत्रिकाएं जयललिता के दबंग व्यक्तित्व के खिलाफ इन दोनों नेताओं के उभरे असंतोष की कहानियां छाप रही हैं। पनरुटी रामचंद्रन ने तो केंद्र में श्रीलंका के मामले पर एमजी रामचंद्रन के प्रवक्ता की भूमिका अदा की थी, इस कारण उन्होंने दिल्ली से संपर्क बनाया हुआ है। दूसरी ओर, नेदुनचेझियन के दिल में तीसरी बार भी मुख्यमंत्री न बन पाने का दर्द है, लेकिन वह जानते हैं कि उनके लिए जयललिता के बिना सत्ता तक पहुंच पाना असंभव है।

लोकसभा में आल इंडिया अन्नाद्रमुक के सांसद और जयललिता गुट के नेता पी कोलंदईवेलु जहां जयललिता को स्व० रामचंद्रन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बताते हैं, वहीं यह उम्मीद भी करते हैं कि स्व० एमजी रामचंद्रन के समय कांग्रेस-इ से जैसा गठबंधन था, वह जारी रहेगा। उनका कहना है, इस संबंध में बातचीत चल रही है, लेकिन यदि यह बातचीत असफल रहती है, तो उन्हें आशा है कि जयललिता गुट अकेले अपने दम पर ८० प्रतिशत सीटें जीत ले जायेगा। दूसरी ओर जानकी गुट भी ऐसी ही उम्मीद बांधे हुए है। उन्हें भरोसा है कि तमिलनाडु की जनता को एक असहाय विधवा के रूप में जानकी रामचंद्रन से सहानुभूति है और इसे लहर का रूप देने के लिए वह सभाओं में भाषण देते हुए रोने भी लगती हैं। ऐसी ही एक सभा में जब उन्होंने रोना शुरू किया, तो श्रोताओं में उपस्थित महिलाओं ने भी फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जयललिता के एक समर्थक कलकंडु पत्रिका द्वारा किये गये जनमत संग्रह का हवाला देते हैं। उसमें जयललिता पहले स्थान पर थीं और स्व० रामचंद्रन की पत्नी होने के बावजूद जानकी तीसरे जबकि शिवाजी गणेशन दूसरे स्थान पर थे। उक्त समर्थक का कहना है कि जानकी को राजनीति नहीं आती और रोने-धोने से सत्ता नहीं मिलती। ये शब्द कांग्रेस-इ छोड़कर तमिलाग मुनेत्र मुन्नै नामक नयी पार्टी बनानेवाले शिवाजी गणेशन के लिए भी चेतावनी हैं, क्योंकि वह भी जनता के जजबातों को उभारने के लिए जनसभाओं में रो देने में जानकी से पीछे नहीं हैं।

सत्ता की दौड़ में शामिल एक नेता डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) के सर्वेसर्वा करुणानिधि हालात का जायजा ले रहे हैं और अभी खुलकर सामने नहीं आये हैं। पिछले चुनावों में उन्हें यद्यपि तीन बार लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ा है, फिर भी उनके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। डीएमके के एक सूत्र का कहना है कि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पायेगी, डीएमके अधिक-से-अधिक ६०-७० सीटें जीत सकती है और समय अनुकूल रहा, तो इन्हीं सीटों के दम पर करुणानिधि सरकार बना ले जायेंगे।

तमिलनाडु में चुनावी माहौल बनता जा रहा है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम भी जोरों पर है। स्व० रामचंद्रन मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर जहां करोड़ों की कमायी के आरोप लग रहे हैं, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मद्रास में राजीव गांधी की तमिल टाइगर्स के चीफ प्रभाकरन से गुप्त बातचीत होती रही है। यद्यपि श्रीलंका स्थित भारतीय राजदूत जेएन दीक्षित ने इसका खंडन किया है, लेकिन ऐसी बातें तमिल टाइगर्स से सहानुभूति रखनेवाले तमिल लोगों का दिल जीतने के लिए कही जा रही हैं। मद्रास के विभिन्न गुटों और पार्टियों से सहानुभूति रखनेवाले अखबार अपने-अपने गुटों व पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुलकर सामने आ गये हैं। सुना जा रहा है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक चो रामास्वामी मूपनार के भाई जीआर मूपनार के धन से शीघ्र ही 'तुगलक टाइम्स' नाम से एक अंग्रेजी दैनिक निकालने जा रहे हैं।

बहरहाल, जयललिता, शिवाजी गणेशन और जानकी के लिए यह चुनाव जीवन-मरण का सवाल बन गया है। या तो यह उन्हें बना देगा या काफी लंबे समय के लिए उन्हें राजनीति के अंधेरे में धकेल देगा। कांग्रेस-इ और मूपनार भी इस चुनाव को इसी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन कोलंदईवेलु का कहना है कि तमिल जनता जागरूक है और वह मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को अच्छी तरह जानती-समझती है। देखना यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है?

—बालाजी अय्यर

आंखफोड़ आपरेशन

रोशनी दी तो नहीं, ले और ली ?

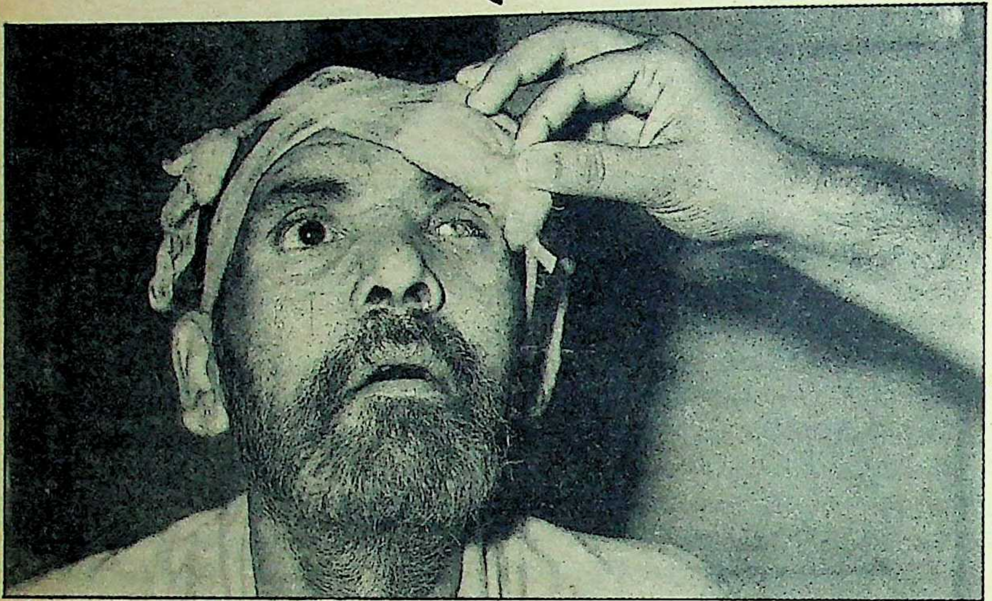

दुर्घटना या लापरवाही ? : ज्योतिविहीन वेंकटरायप्पा

बंगलोर से ८० किमी दूर चितामणि गांव के उन १६४ गरीबों को क्या पता था कि बंगलोर के सुप्रसिद्ध आंखों के अस्पताल 'मिंटो हास्पिटल' से आयी डाक्टरों की टीम द्वारा आयोजित 'नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा' में उनकी आंखों को रोशनी मिलने के बजाय हमेशा-हमेशा के लिए उन्हें अंधकार मिलेगा। पिछले दिनों चितामणि में लायंस क्लब के सहयोग से मिंटो हास्पिटल की 'चल नेत्र चिकित्सा इकाई' ने जो मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया, उनमें से ६५ रोगी अभी भी अस्पताल में बिस्तर पर पड़े अपने भाग्य को कोस रहे हैं। कई रोगियों की तो दोनों आंखों की रोशनी चली गयी है और उनके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया है।

दस वर्षीय कृष्णा चितामणि का रहनेवाला है, वह चौथी कक्षा का विद्यार्थी है। जब वह चार-पांच वर्ष का था, तब उसकी एक आंख में सूई से घाव बन गया था और मोतियाबिंद हो गया था, तभी से उसकी एक आंख की ज्योति चली गयी थी। उसका ५५ वर्षीय पिता वेंकटप्पा भी मोतियाबिंद का शिकार हो गया। वेंकटप्पा ने 'माया' संवाददाता को बताया कि वह गरीबी की वजह से अपना तथा बेटे का आपरेशन करवाने की सोच भी नहीं सकता था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि बंगलोर से बड़े-बड़े डाक्टरों का एक दल चितामणि आ रहा है। यह भी प्रचार किया गया था कि आंखों के इलाज का जो शिविर लगेगा, उसमें आवास और भोजन भी मुफ्त मिलेगा। "हमें क्या पता था कि यह शिविर रही-सही रोशनी भी छीन लेगा। मेरा छोटा-सा बच्चा भी अपाहिज हो गया है।" वेंकटप्पा अपने बच्चे कृष्णा की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहता है।

कोलार जिले के मारपल्ली नामक छोटे से गांव का रहनेवाला चौंसठ वर्षीय वेंकटरायप्पा की स्थिति तो और भी करुणाजनक है। उसकी आंखों में मवाद पड़ चुकी है। 'माया' प्रतिनिधि के साथ गये नगर के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डा० नरपतिसिंह सोलंकी कहते हैं कि वेंकटरायप्पा ही नहीं, वार्ड में भरती एक भी रोगी की रोशनी लौटने के आसार नजर नहीं आते। अब उन्हें अस्पताल में सप्ताह-दो सप्ताह रखकर मरहम पट्टी करना केवल झूठा दिलासा भर देना है। पचास वर्षीय हनुमंतरायप्पा की एक आंख से थोड़ा-थोड़ा दिखता था और वह अपने बच्चों का सहारा था, परंतु आपरेशन के बाद तो उसकी दोनों आंखें चली गयीं। उलटा वह बच्चों पर बोझ बन गया है। वह अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा, कहते-कहते उसका गला भर आता है। नारायण रेड्डी, इरप्पा तथा महिला रोगी मलक्का, रतनम्मा, नारायनम्मा, हनुमक्का आदि की भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक दास्तान है जो अपने जीवन को संवारने की आस लेकर शिविर में आये थे और अब अपने ही किये पर माथा पीट रहे हैं।

नायाब हादसा: सरकारी मिंटो अस्पताल की उक्त 'चल नेत्र चिकित्सा' इकाई का प्रमुख कार्य ही आंखों की चिकित्सा के शिविर आयोजित करना है। बताया जाता है कि इस इकाई ने जितने भी शिविर अब तक आयोजित किये, उनमें कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। डाक्टरों का कहना है कि आपरेशन के पूर्व तथा बाद में जितनी भी सावधानी बरती जानी चाहिए थी, उतनी बरती गयी थी। अचानक इतनी बड़ी संख्या में केस बिगड़ने का कारण मात्र संक्रमण (इंफेक्शन) ही हो सकता है।

चितामणि के इस 'मुफ्त शिविर' के इंचार्ज थे डा० एचएन तिम्मा सेट्टी। उनको शल्य क्रिया में चितामणि के ही एक स्थानीय डाक्टर जगन्नाथ सेट्टी, सहायक सर्जन डा० नारायणा, पोस्ट ग्रेजुएट की दो छात्राओं—डा० प्रभा तथा डा० चंद्रिका ने सहयोग दिया। चितामणि के स्थानीय डाक्टर ने बाद में इसका खंडन किया कि आपरेशन करनेवालों में वह भी शामिल थे। डा० तिम्मा सेट्टी ने कहा कि उक्त इकाई द्वारा अब तक हजारों सफल आपरेशन किये जा चुके हैं, इसलिए डाक्टरों को दोष देना उचित नहीं है। वह बताते हैं कि अस्पताल की इस यूनिट ने १९८१-८२ में २७ शिविर आयोजित कर २९१४ नेत्र रोगियों के आपरेशन किये। १९८२-८३ में ३३९५, वर्ष १९८३-८४ में ४७२५, १९८४-८५ में ५१२५, १९८५-८६ में ४९७१ तथा वर्ष १९८६-१९८७ में ४१२६ आपरेशन इस इकाई ने सफलतापूर्वक संपन्न किये।

डाक्टरों का कहना है कि निश्चित रूप से यह दुर्घटना संक्रमण की वजह से हुई है, इसमें आपरेशन करनेवाले डाक्टरों की कोई गलती नहीं है। 'स्यूडोमोनास' नामक विषाणु के संक्रमण से यह हादसा हुआ है। आपरेशन करने वाली टीम के डाक्टरों का कथन तो यह है, परंतु विश्व रिकार्ड (अब तक ५ लाख से ज्यादा आंखों के आपरेशन करनेवाले) स्थापित करने वाले डा० एमसी मोदी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि संक्रमण किसी विशेष विषाणु द्वारा अटैक करने से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि शल्य क्रिया (आपरेशन) में काम लिये जानें वाले उपकरणों को ठीक तरह से विषाणुरहित (स्टर्लाइज) न किया गया हो, तब भी ऐसा होना संभव है। इसके साथ-साथ दो दिन पूर्व ही आपरेशन थियेटर (अथवा वह कमरा जहां आपरेशन करने हों) की भलीभांति सफायी करवाना तथा उन रोगियों की सूक्ष्मता से जांच करना, जिनका आपरेशन करना हो, अति आवश्यक है। यदि आपरेशन ठीक तरीके से न किये गये हों, तब भी संक्रमण की संभावनाएं बनी रहती हैं। नगर के एक अन्य सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डा० नरपतसिंह सोलंकी से 'माया' प्रतिनिधि ने जब यह पूछा कि क्या इस अनहोनी से बचा भी जा सकता था, तो डा० सोलंकी ने कहा कि आंखों के आपरेशन में कोई भी गड़बड़ी हुई हो, तो दो दिन में इसका पता डाक्टर को अवश्य लग जाता है और डाक्टर तत्काल उपाय करके आंखें बचा सकता है। संक्रमण चाहे उपकरणों के माध्यम से हुआ हो, या किसी दवा से हुआ हो, इसका पता लगते ही उपाय नहीं किये गये, ऐसा रोगियों से की गयी बातचीत से पता चलता है, अन्यथा इतनी बड़ी तादाद में केस कतई नहीं बिगड़ते।

डाक्टर चाहे कोई भी सफाई पेश क्यों न करें, कैसी भी दलील अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए क्यों न दें, परंतु यदि डाक्टर लापरवाही नहीं बरतते, तो शायद इतने गरीबों की आंखों की रोशनी नहीं जाती, वे अंधे न होते।

—श्रीकांत पाराशर

ार्ज थे डा०
क्रिया मे
र जगन्नाथ
ोस्ट ग्रेजुएट
चंद्रिका ने
डाक्टर ने
आपरेशन
तिम्मा सेट्टी
जारों सफल
टरों को दोष
स्पताल की
र आयोजित
शन किये।
में ४७२५,
में ४६७१
ापरेशन इस

त रूप से यह
में आपरेशन
नहीं है।
मण से यह
ली टीम के
श्व रिकार्ड
ि आपरेशन
सी मोदी ने
कि संक्रमण
रने से ही
शल्य क्रिया
पकरणों को
) न किया
इसके साथ-
(अथवा वह
भलीभांति
सूक्ष्मता से
हो, अति
े से न किये
बनी रहती
शेषज्ञ डा०
ने जब यह
जा सकता
े आपरेशन
इसका पता
टर तत्काल
क्रमण चाहे
सी दवा से
ीं किये गये,
चलता है,
कतई नहीं

क्यों न करें,
रने के लिए
नहीं बरतते,
ोशनी नहीं

त पाराशर

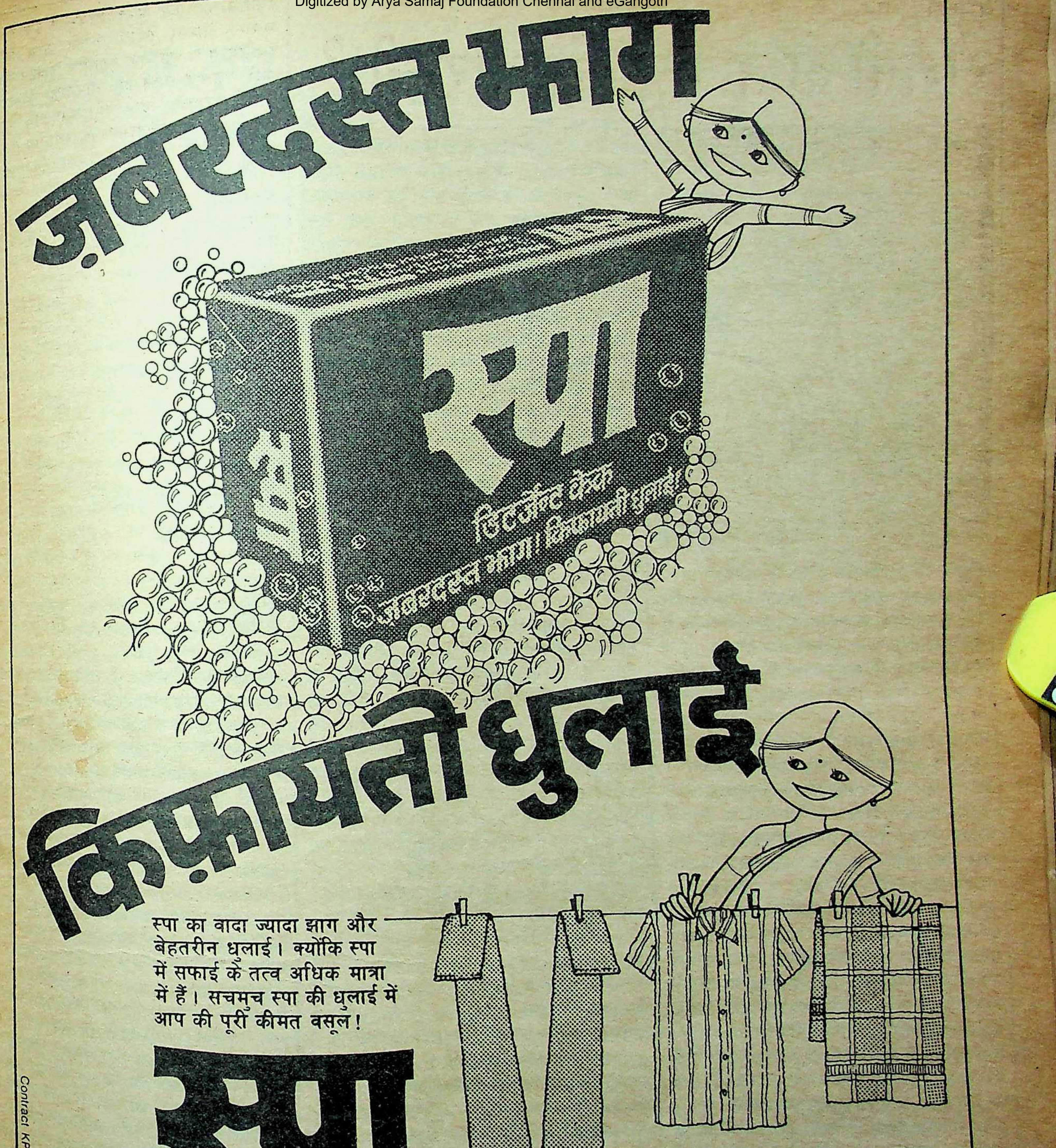
ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेन्ट केक
ज़बरदस्त झाग। किफ़ायती धुलाई।
किफ़ायती धुलाई
A Kusum Product
Contract KP 96-86 HIN

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा
डिटर्जेन्ट केक

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

तस्वीर की राजनीति !

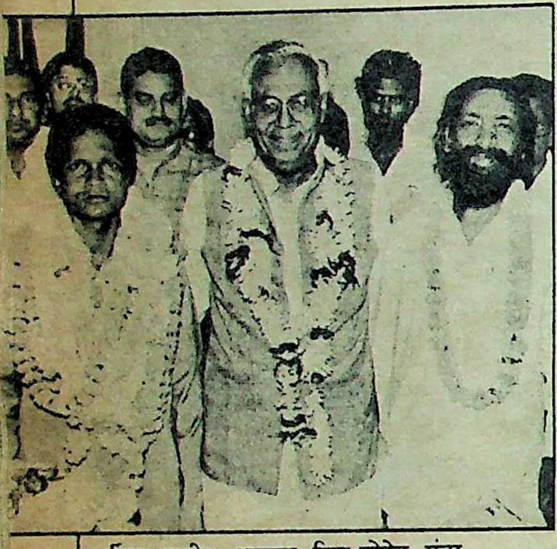

चर्चित तस्वीर : आजाद, शिबू सोरेन, मुंडा

मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने आदिवासी राजनीति के अपने पत्ते को महज एक तस्वीर के जरिये कुछ इस तरह से खेला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता यह सफाई दे-देकर परेशान हैं कि कांग्रेस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है।

दरअसल, हाल में हुए विधान परिषद के चुनाव के बाद कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों के बजाय जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजयी प्रत्याशी छत्रपति शाही मुंडा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के संग मुख्यमंत्री आजाद की तस्वीर पटना के लगभग सभी प्रमुख दैनिकों में छपी, तो राजनीतिक हलके में लोगों के कान खड़े हो गये। सरकार की तरफ से परिषद चुनाव के बाद अखबारों को सिर्फ यही एक तस्वीर जारी क्यों की गयी, इसका मकसद पुराने राजनीतिक खिलाड़ियों को समझने में देर नहीं लगी। दूसरी तरफ इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आजाद के पिंजरे का आदिवासी पंछी हो गया है। स्वयं आजाद ने भी कंई मौकों पर यह टिप्पणी की कि मोर्चा को वह कांग्रेस का आदिवासी विंग बनायेंगे। जाहिर है इस धुआंधार सरकारी प्यार से झारखंड मुक्तिमोर्चा के नेता आक्रामक खंडन के बजाय विनय भाव से सफाई देने लगे कि आजाद सरकार से उनका कोई रिश्ता नहीं पनपा है। विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री आजाद ने मोर्चा प्रत्याशी छत्रपति मुंडा को जिताने के लिए न सिर्फ इंका के अठारह वोट जुगाड़ दिये, बल्कि डा० जगन्नाथ मिश्र की कम्युनिस्ट राजनीति को भी झटका देकर 'दोहरा खेल' खेला। दरअसल, पिछले दो बार से कम्युनिस्ट पार्टी के बुजुर्ग नेता और अपने सगे मौसेरे भाई चन्द्रमोहन मिश्र को जगन्नाथ मिश्र कांग्रेसी मतों व निर्दलीय विधायकों के मतों को जोड़-तोड़ कर परिषद चुनाव में कामयाबी दिलाने में कारगर होते रहे थे। पर इस बार मोर्चा के आदिवासी नेताओं से गले मिलकर आजाद ने चन्द्रमोहन मिश्र को चित्त कर जगन्नाथ मिश्र को भी झकझोर दिया है। परिषद चुनाव २६ मार्च को था और २८ मार्च की आधी रात तक कम्युनिस्ट प्रत्याशी चन्द्रमोहन मिश्र के लिए जगन्नाथ मिश्र वोट जुटाने में लगे रहे थे। चन्द्रमोहन मिश्र जगन्नाथ मिश्र के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न थे। चन्द्रमोहन की पराजय से नाराज जगन्नाथ ने अपने शुभचिंतकों के बीच यह टिप्पणी भी की कि 'लगता है इनसे (आजाद) मुझे लड़ना ही पड़ेगा'।

संथालपरगना में शिबू सोरेन का प्रभाव है और मोर्चा के अधिकांश विधायक दुमका जिले के ही हैं। शिबू के अखबारों में प्रकाशित उस बयान को भी काफी सुर्खियां मिलीं कि—'आजाद भी चूंकि संथालपरगना क्षेत्र के ही हैं, इसलिए आदिवासियों को उनसे काफी आशाएं हैं'। दरअसल, आजाद से तालमेल कर चलना शिबू की मंजबूरी भी है, क्योंकि सरकार से नरम रिश्ते कायम करके ही वह फिर आनेवाले चुनाव में आठ नौ विधायकों की अपनी जमात को चुनावी दंगल में निकाल पायेंगे।

परिषद चुनाव में इंका से छत्रपति मुंडा को इकतरफा फायदा नहीं मिला। राज्यसभा में अपने छठे प्रत्याशी दयानंद सहाय के लिए इंका ने भी मोर्चा के नौ विधायकों के वोट लिये। जाहिर है चुनावी सहयोग पारस्परिक था। पर मोर्चा का सहयोग ले-देकर इंका ने जो दूना लाभ लिया है उससे राजनीतिक गलियारों में यह माहौल बन गया है कि मोर्चा कांग्रेस के काबू में आ गया है। एक पुराने राजनीतिक खिलाड़ी का विश्लेषण है कि इंका ने सार्वजनिक रूप से मोर्चा पर अपना राजनीतिक विश्वास जता कर मोर्चा को संदेह और सफाई के कठघरे में ला खड़ा किया है। आदिवासी राजनीति वैसे भी इन दिनों भयानक अन्तर्कलह की शिकार है। नवोदित संगठन झारखंड समन्वय समिति व अखिल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से झारखंड मुक्तिमोर्चा का घनघोर तनाव चल रहा है। यों इन तीनों संगठनों की मांग एक ही है—अलग झारखंड ! पर एक मुद्दे के बावजूद नेतृत्व के अहं का टकराव है। इन आदिवासी संगठनों की लड़ाई को और हवा देकर कांग्रेस पार्टी फायदा ले सकती है। मुक्तिमोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन 'माया' से कहते हैं, "कांग्रेस से बस हमारी चुनावी मैत्री थी। अगर आजाद सरकार आदिवासियों के हित में कार्य करेगी, तो उसकी सराहना की जायेगी, वरना नहीं।"

बहरहाल, आदिवासी राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कांग्रेस की सवारी कहीं कागज की नाव में आग की सवारी तो नहीं? आदिवासी राजनीति के एक महीन जानकार रोचक टिप्पणी करते हैं कि हर सूरत में घाटा आग को नहीं है।

—पटना ब्यूरो

अशफाक अंसारी

एक चक्कूबाज मंत्री ?

राज्यमंत्री अशफाक अंसारी को सत्ताविहीन करने के लिए उनके विरोधियों ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है। यद्यपि चाकूबाजी के इस मुकदमे में सुलह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है। यह चाकूबाजी का मामला क्या है और इसने कौन-सा राजनीतिक मोड़ ले लिया है?

बिहार के लघु ग्रामीण व कुटीर राज्यमंत्री अशफाक अंसारी को एक आपराधिक मामले के तहत ५ दिसंबर, १९८३ को जब अठारह दिनों के लिए हिरासत में रहना पड़ा था, तो उस समय उनकी राजनीतिक हैसियत दरभंगा शहर के एक साधारण वार्ड कमिश्नर की थी। चक्कूचालन के मामले में उनकी यह संक्षिप्त हिरासत उनके आगामी राजनीतिक जीवन के लिए तबाही लेकर आयेगी, उस समय संभवतः स्वयं अशफाक को भी इसका आभास नहीं रहा होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि आजाद मंत्रिमंडल के आगामी विस्तार के मौके पर कोई आश्चर्य नहीं कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर अशफाक की राज्यमंत्री की कुरसी छीन ली जाये। यों २५ अक्तूबर, १९८३ को लहेरियासराय थाने में अशफाक अंसारी व अन्य पर धारा १४३, १४९, ३०७, ३२४, ३२६ व ३४१ के तहत मुहम्मद बाबू जान नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज प्राथमिकी (४०१/८३) का मामला दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से लेकर पटना उच्च न्यायालय तक उठकर आखिरकार ६ मार्च, १९८७ को समाप्त तो हो चुका है, पर अशफाक के विरोधी इसके बावजूद उनको अपराधी ठहराने पर तुले हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने राजनीतिक दबाव डाल कर मामले को रफा-दफा करवाया था, जिसमें बिंदेश्वरी दुबे की सरकार ने भी उनकी मदद की थी।

दरभंगा के शाहगंज मुहल्ले के शमशे आलम व हायाघाट में हेल्थवर्कर के रूप में कार्यरत उर्मिला झा जो सपरिवार उसी मुहल्ले में रहती थी, पर प्राणघातक हमला करने का मामला अशफाक के

विरुद्ध जब बाबू जान ने दर्ज कराया, तो लहेरियासराय के थाना प्रभारी ने उक्त प्राथमिकी के आधार पर ५ दिसंबर, १९८३ को अशफाक सहित अन्य लोगों को जेल भेजा था। दरभंगा के बेता मुहल्ले में जहां अशफाक का घर है, के लोग दृश्य को आज भी नहीं भूले हैं, जब पुलिस अशफाक को सबके सामने बांधकर ले गयी थी। ६ दिसंबर '८३ को जब अदालत में अशफाक की जमानत के लिए अर्जी दी गयी, तो उसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि मामले में चूंकि अशफाक का ही नाम प्रमुख है, इसलिए गंभीर आरोप की स्थिति में जमानत की मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

फिर २८ अप्रैल को लहेरियासराय पुलिस ने इस मामले में अशफाक सहित अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उस आरोप पत्र के आधार पर कुछ कार्रवाई होती कि अचानक आरक्षी अधीक्षक ने मामले में एक अजीबोगरीब हस्तक्षेप किया कि आरोप पत्र पर कोई कार्रवाई न की जाये। जाहिर है अदालत के सामने धर्मसंकट की स्थिति थी। एक तरफ पुलिस का आरोप पत्र और दूसरी तरफ अपनी पुलिस के ही आरोप पत्र को न मानने की आरक्षी अधीक्षक की पेशकश। बहरहाल, मामला फिर आरक्षी उपाधीक्षक को सौंपा गया। आरक्षी उपाधीक्षक ने पूरे मामले पर अंतिम रपट देकर मामला समाप्त कर दिया। लेकिन आरोपकर्ता चैन से नहीं बैठे। मामला फिर अदालत में गया। न्यायिक दंडाधिकारी व अतिरिक्त न्यायाधीश (पांच) के फैसले में काफी मतभेद हुआ। न्यायिक दंडाधिकारी जहां पूरे मामले को समाप्त कर प्राथमिकी में नामजद लोगों को मुक्त कर देने के पक्ष में थे, वहीं अतिरिक्त न्यायाधीश (पांच) इस बात पर अडिग थे कि हर सूरत में इस मामले पर 'कोगनीजेंस' (हस्तपक्षेप के योग्य अपराध) लिया ही जाय। अतिरिक्त न्यायाधीश के इस विपरीत फैसले से घबड़ाये अशफाक पटना उच्च न्यायालय में गये, जहां उन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के आदेश पर स्थगन आदेश ले लिया। इसी बीच बिन्देश्वरी दुबे का दरबार कर अशफाक ने दुबे को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि बिहार सरकार अशफाक के बचाव में कूदे। यह सब अभियान चल ही रहा था कि बाबू जान, शमशे आलम से अशफाक ने आरजू मिन्नत कर समझौता किया और इस बात के लिए राजी कर लिया कि बाबू जान अदालत में लिखकर दे दे कि उन दोनों में अब सुलह हो गयी है, सो मामला समाप्त किया जाये।

विरोधियों का तर्क: बहरहाल, मामले की वापसी तो बाबू जान की अर्जी पर हो गयी, पर अब भी उनके विरोधियों की नजर में एक अहम सवाल अनुत्तरित रह गया कि अशफाक अंसारी सचमुच आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं या नहीं? वे कहते हैं कि बाबू जान ने सुलह की अर्जी में इसका जिक्र कहीं नहीं किया कि अशफाक से सम्बन्धित उसकी शिकायत गलत थी। लिहाजा, सुलह-सपाटे के बावजूद अशफाक अपने बारे में एक अच्छे आदमी का सर्टिफिकेट नहीं पा सके। अब यहां सिर्फ दो बातें हैं कि १९८३ के उस हादसे में क्या अशफाक ने सचमुच खुद शमशे आलम को छुरा मारा था? अगर ऐसा है, तो अशफाक को मंत्री-पद से जाना ही होगा या फिर आरोपकर्ता बाबू जान यह कबूलें कि उन्होंने अशफाक के बारे में जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी, वह गलत थी। अगर बाबू जान अपनी प्राथमिकी को गलत ठहराते हैं, तब कार्रवाई उन्हीं पर होनी चाहिए और अगर बाबू जान ऐसा नहीं करते, तो अशफाक का बचना मुश्किल है। अशफाक अगर दरभंगा के एक महज मामूली वार्ड कमिश्नर होते, तो शायद सब कुछ चल जाता, पर एक राज्यमंत्री की कुरसी पर बैठे अशफाक को प्रदेश के लोग शायद ही बरदाश्त कर सकें। यों अभी आरोपकर्ता व इस मामले से सम्बद्ध अन्य आहत व्यक्ति कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं हैं। अशफाक ने 'माया' से कहा भी कि वे सभी लोग अब मेरे साथ घूमते हैं। पर अशफाक के आलोचक कहते हैं कि जब एक विधायक की हैसियत का ही रोब गालिब कर अशफाक मामला खतम कराने में कामयाब हो गये, तो फिर अब तो वह मंत्री हैं। भला उनके खिलाफ अब कौन मुंह खोलेगा?

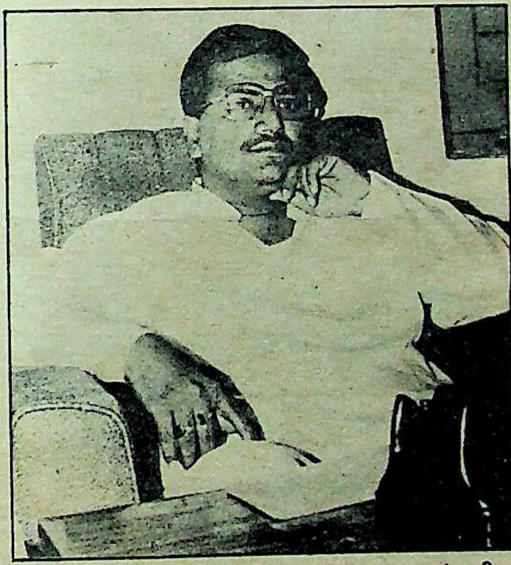

विरोधियों की मुहिम के शिकार: अशफाक अंसारी

बहरहाल, यह सही है कि अशफाक अदालत से बरी हो चुके हैं, पर जन-अदालत में उन्हें यह साफ करना होगा कि वह एक चक्कूबाज नहीं, बल्कि सीधे-सच्चे इंसान हैं। सार्वजनिक जीवन में यह बात काफी अहमियत रखती है, जिसे महज खतम हो चुके मुकदमे की मोटी फाइल दिखाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

९ जनवरी, १९८५ को दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जो निर्णय दिया था, वह अशफाक के पक्ष में था। अपनी सफाई में अशफाक इसी फैसले का सगर्व हवाला देते हैं, क्योंकि इसमें अशफाक की तारीफ की गयी थी। पर इस फैसले में भी आलोचकों को लगता है कि मान्य न्यायाधीश ने पुलिस की जिस भूमिका की चर्चा की है, उससे ऐसा लगता है कि अशफाक ने घालमेल करके मामले को पुलिस के स्तर पर कमजोर करवा दिया था। वह फैसला यों है: "पुलिस द्वारा दो विरोधाभासी बयान देने की वजह से उक्त मामला अदालत में सुनवाई के लिए आया। एम बाबू जान के लिखित बयान के आधार पर ही अशफाक अंसारी, रजा, ऐनुल, इकबाल व अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा १४३, १४९, ३४१, ३२६, ३०७ एवं ३२४ का मामला दायर किया गया। जांच करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में आरोप पत्र को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई होने को ही थी कि आरक्षी अधीक्षक ने अदालत से अनुरोध किया कि आरोप पत्र को ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लिया जाये। इसके बाद मामले में पूरक बयान व रपट देने की कोशिश की गयी। अंतिम रपट में कोई भी मामला स्पष्ट नहीं हुआ। लिहाजा, पुलिस रपट को देखते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया। मैंने दोनों पक्षों के वकील व सरकारी वकील की बातें ध्यान से सुनीं।

"प्राथमिकी के अनुसार मामला २४ अक्तूबर '८३ की रात सवा आठ बजे का है। एम बाबू जान उस समय अपने घर लौट रहे थे। अचानक हायाघाट ब्लाक में कार्यरत उर्मिला झा के मकान के भीतर उन्हें गोली चलने की आवाज सुनायी पड़ी। तत्काल बाबू जान उस के आंगन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शमशे आलम आंगन में तड़फड़ा रहा है और अशफाक अंसारी उसके पेट में छुरा भोंक रहे हैं। साथ-साथ फसुज्जमा व शब्बीर शमशे आलम पर फरसा से वार कर रहे थे। रजा, ऐनुल और इकबाल भी घायल व्यक्ति को छुरा मार रहे थे। बाबू जान ने जब हमलावारों को रोकना चाहा, तो अशफाक अंसारी ने धमकी दी कि मेरे काम में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की, तो नतीजा बुरा होगा। नतीजतन, बाबू जान भयवश बाहर निकल गये। इस बीच शोरगुल तेज होने से वहां काफी भीड़ जमा हो गयी। धीरे-धीरे हमलावर भाग खड़े हुए। घायल व्यक्ति को अस्पताल (डीएमसीएच) ले जाया गया। घायल व्यक्ति बेहोश था, सो उस समय पुलिस बयान नहीं ले सकी। कई घंटे बाद रात के एक बज कर पन्द्रह मिनट पर उसका बयान दर्ज किया गया।

"अब दो रपट सामने आ जाने से देखना यह है कि सही कौन सी है? शमशे आलम के शरीर पर जख्म के अनगिनत निशान थे। २४ अक्तूबर, १९८३ की रात में साढ़े दस बजे घायल व्यक्ति की जांच डाक्टरों ने दरभंगा मेडिकल कालेज में की। उसकी आंत व गुप्तांगों में छुरा घुसेड़ा गया था। घायल व्यक्ति गंभीर खतरे में था। उसके सिर में भी चोट लगी थी। दरभंगा के आरक्षी अधीक्षक के आदेश के बाद पुलिस ने अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया।

"विद्वान वकीलों ने अदालत का धयान आकर्षित किया कि सभी चश्मदीद गवाहों ने घटना की सही जानकारी दी है। पुलिस के जांच अधिकारी ने घटना स्थल पर खून के छींटे भी देखे थे। पुलिस ने उर्मिला झा और उसके लड़के अखिलेश कुमार झा के

बयान भी लिये। दोनों ने कहा कि अपराधी जमात ने उनके घर में घुसकर शमशे आलम पर हमला किया। उर्मिला झा ने आगे कहा कि एक अपराधी ने अपनी पिस्तौल से हवा में दो चक्र गोलियां भी दागीं। यों इन गवाहों में से किसी ने भी अपराधियों को पहचानने से इनकार किया। उर्मिला झा का मकान बेता मुहल्ले में है। पुलिस ने उसी मुहल्ले के तजेमुल हुसैन का बयान लिया। हुसैन के अनुसार अंधेरे की वजह से वह किसी को पहचान नहीं सका। मदन मोहन यादव ने घटना का पूरा जिक्र किया है। वह उसी मुहल्ले का रहने वाला है। उसके अनुसार घटना के समय वह सिनेमा देखने जा ही रहा था कि शोर सुन वह घटनास्थल पर पहुंचा। उसने कहा कि वह हमलावरों को पहचानता है। उसके मुताबिक उसने अशफाक के हाथ में पिस्तौल देखी। मुख्य समस्या यह है कि अभियुक्त के हाथ में छुरा था या पिस्तौल, इसका पता लगाने के लिए घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी का होना आवश्यक था। उसके अनुसार शमशे आलम ने 'बुनकर समिति, बेता' की ओर से अशफाक पर लाखों रुपए के घपले का मामला ठोंक रखा था। नतीजतन अशफाक जो पेशे से प्रोफेसर हैं, ने शमशे आलम से प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा अपराध किया।

"कमरुद्दीन उर्फ कोलन का बयान भी पुलिस ने लिया। अपने बयान में उसने अभियुक्त का नाम साफ-साफ बताया। इस प्रकार जांच अधिकारी के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं। पर दूसरी ओर आरक्षी उपाधीक्षक ने जब मामले की तहकीकात की, तो पाया कि अशफाक को इसमें सुनियोजित रूप से फंसाया गया है। इसके तत्काल बाद आरक्षी अधीक्षक ने मामले को देखा-परखा, आरक्षी उपाधीक्षक की रपट देखी, फिर आगे जांच का आदेश दिया। आखिरकार पुलिस की अंतिम जांच रपट में कुछ नहीं पाया गया।

"अभियुक्त अशफाक अंसारी मिथिला विश्वविद्यालय के मिल्लत कालेज में व्याख्याता हैं। सन् १९८० से वह वार्ड कमिश्नर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा जघन्य अपराध किया होगा, गलत है। यदि उन्हें अपराध करना ही होता, तो वह दूसरे से करवा सकते थे।"

दरभंगा के न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने फैसले में आगे लिखा है, "इस घटना के सभी चश्मदीद गवाह शाहगंज बेता के बाशिंदा हैं। फिल्म देखने जाते समय उन लोगों ने शोरगुल सुना। यह अपने में हास्यास्पद है। एक गवाह तजेमुल हुसैन से पूछतांछ की गयी, तो उसने अभियुक्तों को पहचानने से इनकार कर दिया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपराध जिस समय हुआ, उस समय चारों तरफ घुप्प अंधेरा था। ऐसे में अपराधियों को पहचानना मुश्किल था। केस डायरी से जानकारी मिलती है कि सभी चश्मदीद गवाह जख्मी शमशे आलम के अंतरंग लोग हैं। शमशे आलम सीपीएम का सक्रिय सदस्य है। शमशे अकसर उर्मिला झा के घर जाया करता था। उर्मिला के अनुसार शमशे 'पियरलेस कंपनी' में क्षेत्रीय पदाधिकारी था और उर्मिला का पुत्र भी उसी पियरलेस कंपनी में कार्यरत था। इस लिहाज से शमशे आलम का उसके घर जाना-आना था। उर्मिला अपने घर में दो लड़कों व एक गूंगी बेटी के साथ रहती है। उसकी गूंगी बेटी विवाहित है। केस डायरी के मुताबिक शमशे कई केस में फंसा हुआ है। उस पर धारा ३७९ एवं ३८० के तहत लहेरियासराय में केस भी है। (केस नं० ५-६/७९) साथ ही धारा ३७५ के तहत एक केस (केस नं० १८०/८१), ३७९ एवं ३२३ के तहत दूसरा केस है। जख्मी शमशे आलम कई मामलों में फंसा हुआ है, इस लिहाज से उसके कई दुश्मन भी रहे होंगे। जांच में पता लगा कि शमशे का अवैध सम्बन्ध उर्मिला की गूंगी बेटी से रहा है, जिससे मुहल्ले के लोग तंग आ चुके थे।"

न्यायिक दंडाधिकारी आगे कहते हैं, "जहां तक अवैध संबंध का सवाल है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, पर इस बात के पक्के सबूत हैं कि शमशे पर कई मुकदमे हैं। यही नहीं जांच अधिकारी को अशफाक ने बताया कि घटना के कुछ दिन पहले ही उन्होंने शमशे आलम के विरुद्ध धारा ३७९ के तहत लहेरियासराय थाने में एक केस (केस न० ३८०/८३) दर्ज कराया था। नतीजतन, इस कांड में शमशे ने फंसाने के इरादे से उनका नाम दे दिया। हर बिन्दु से मामले की मैंने जांच की। निस्संदेह शमशे आलम के शरीर पर अनगिनत जख्म के निशान हैं। सारे गवाह 'इत्तफाकन गवाह' हैं जो बेता मुहल्ले के ही हैं। स्थानीय गवाह में एक तजेमुल हुसैन है। तजेमुल ने किसी भी अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। लिहाजा, ऐसी संभावना है कि शमशे आलम को दूसरे लोगों ने आहत किया हो। पुलिस द्वारा जो पूरक रपट पेश की गयी है, उसे गलत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसकी छानबीन की है। पूरक रपट जो 'फाइनल रपट' है, के अनुसार कोई मामला नहीं बनता। अभियुक्त को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त किया जाता है।"

अशफाक अंसारी चाहे जितनी भी सफाई दे लें, पर गड़े मुर्दे की गंध से वह अब बच नहीं पा रहे। अशफाक के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि १९८३ की इस आपराधिक गतिविधि में वह नहीं थे, क्योंकि महज बाबू जान से सुलहनामे का कागज उन्हें बेदाग साबित नहीं कर सकता। सुलह की अर्जी में कहीं भी बाबू जान ने यह नहीं कहा है कि अशफाक उस कांड में नहीं थे। उस अर्जी में बस इतना ही है कि मित्रों व शुभचिंतकों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ है। बहरहाल, अशफाक अभी इस उखड़े हुए मुर्दे को दबाने के लिए जहां परेशान थे कि फिर दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिवकुमार मिश्र नामक एक व्यक्ति ने अपने ८० वर्षीय मालिक पशुपतिनाथ चौधरी के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें दरभंगा जिला इंका अध्यक्ष के अतिरिक्त अशफाक का भी नाम है।

बहरहाल आगे मामला बढने के बाद सुलह-समझौता भी हो गया, पर इसके बावजूद अशफाक पाकसाफ नहीं हो पा रहे हैं। अशफाक ने 'माया' से कहा, "मेरे राजनीतिक दुश्मन एक खतम हो चुके मामले को बेवजह उठा रहे हैं। विधानसभाई चुनाव क समय भी इन्हीं तत्वों ने मेरे खिलाफ दिल्ली से पटना तक यह मामला उछाला। पर बात कुछ नहीं थी, सो मुझे टिकट भी मिला और मैं जीता भी।" अशफाक को इस बात की पक्की आशंका है कि डा० जगन्नाथ मिश्र का खेमा उनके खिलाफ जुटा हुआ है, क्योंकि गत विधानसभाई चुनाव में जगन्नाथ समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रामाश्रय राय को उन्होंने पराजित किया था। बहरहाल, अशफाक अंसारी चाहे जितनी भी सफाई दे लें, पर गड़े मुर्दे की गंध से वह अब बच नहीं पा रहे। अशफाक के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि १९८३ की इस आपराधिक गतिविधि में वह नहीं थे, क्योंकि महज बाबू जान से सुलहनामे का कागज उन्हें बेदाग साबित नहीं कर सकता। सुलह की अर्जी में कहीं भी बाबू जान ने यह नहीं कहा है कि अशफाक उस कांड में नहीं थे। उस अर्जी में बस इतना ही है कि मित्रों व शुभचिन्तकों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ है। बहरहाल, अशफाक अभी इस उखड़े हुए मुर्दे को दबाने के लिए जहां परेशान थे कि फिर दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिवकुमार मिश्र नामक एक व्यक्ति ने अपने ८० वर्षीय मालिक पशुपतिनाथ चौधरी के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें दरभंगा जिला इंका अध्यक्ष के अतिरिक्त अशफाक का भी नाम है। पशुपतिनाथ मुख्यमंत्री के समधी के पिता हैं। उनका अपने पुत्र भरत चौधरी से मनसुटाव रहता है। कुछ लोगों ने बाप-बेटों में सुलह कराने की कोशिश की, तो तनाव बढ़ा और आखिरकार पशुपति ने नौकर के जरिये अपने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। ८० वर्षीय पशुपति कोई सुंदर युवती तो थे नहीं कि उनका अपहरण करने में किसी को दिलचस्पी होती। यह मामला नाराज बाप-बेटे का है। अशफाक को इससे एक बढ़िया बहाना भी मिला है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ कैसे-कैसे मामले बनाते रहते हैं। पर लाख सफाई के बावजूद १९८३ के छुरेबाजी के मामले को झुठला पाने में वह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।

बिहार के एक राजनीतिक मजाकिये का कहना है कि अशफाक ने राजनेताओं के आपराधिक स्तर का हनन किया है महज एक चाकूबाजी जैसी सड़कछाप वारदात करके। अशफाक को जाना ही चाहिए। पर कब? अशफाक विरोधी लॉबी मुख्यमंत्री को सहमत करने में जुटी हुई है।

—विकास कुमार झा

ठाकरे का हुकुमनामा

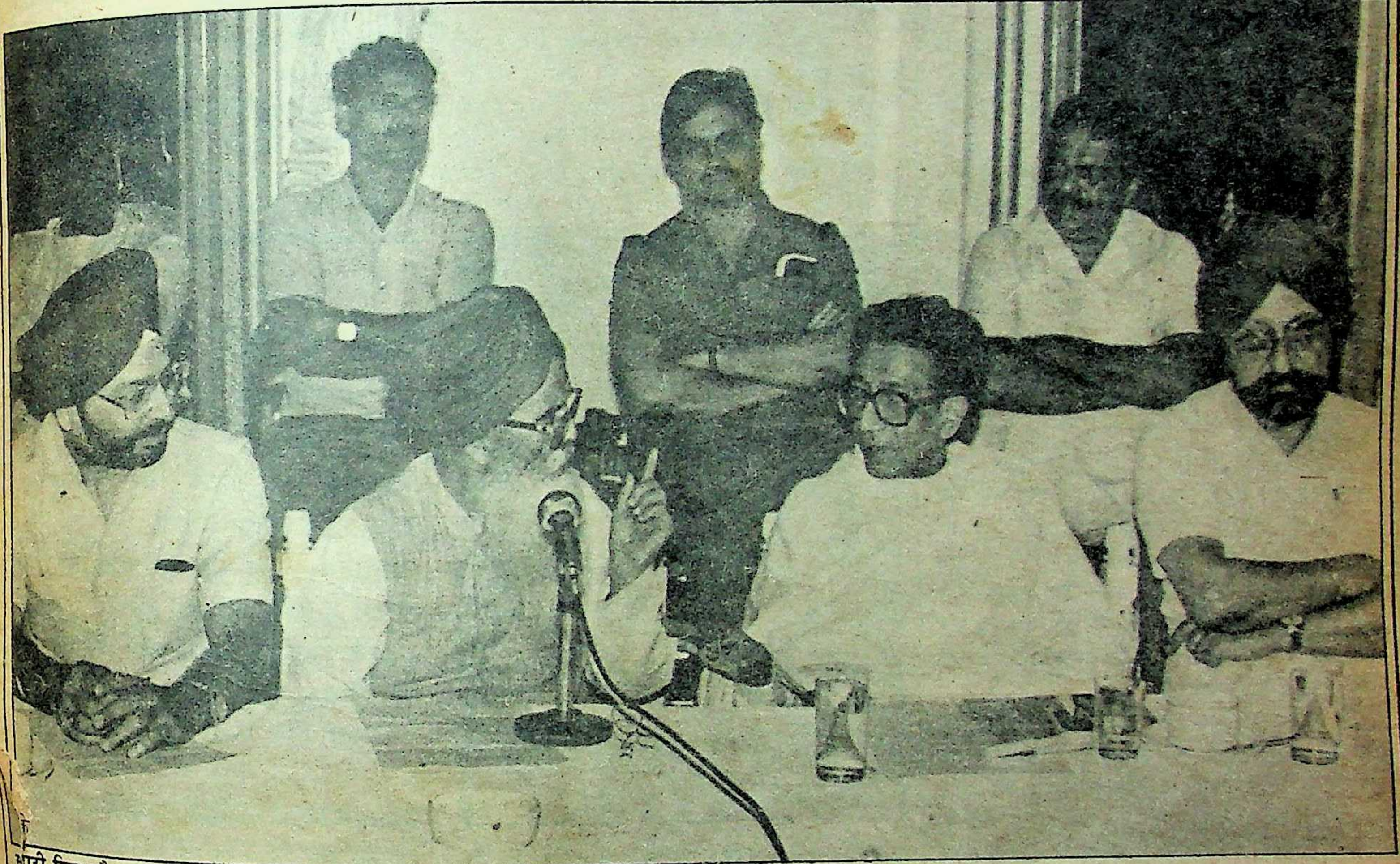

सारी सिख कौम अलगाववादी नहीं : बाल ठाकरे से सिख प्रतिनिधियों की बातचीत

श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या की प्रतिक्रियास्वरूप जब देश के अधिकांश हिस्सों में सिख अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उस समय बंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के आदेश पर शिव-सैनिक सिखों और उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन हाल ही बाल ठाकरे ने सिखों के आर्थिक बहिष्कार का राष्ट्रघाती नारा क्यों लगाया ? इस आरोप में कितना दम है कि उस वक्त ठाकरे ने सिखों की सुरक्षा के लिए सिखों से मोटी रकम वसूली थी। क्या बंबई के सिखों का आर्थिक बहिष्कार करने से पंजाब में आतंकवादी हत्याएं रुक जायेंगी ? क्या बाल ठाकरे ऐसी धमकियां देकर आतंकवादियों के अलगाववादी मंसूबों को ही परवान चढ़ा रहे हैं ? क्या महाराष्ट्र सरकार में बाल ठाकरे पर अंकुश लगाने का दमखम है ?

पंजाब में आतंकवादी हत्याओं से पिछले दो वर्षों से बेहद संतप्त तथा भीतर-ही-भीतर कुढ़ रहे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने इस नासूर के इलाज के लिए महाराष्ट्र के सिखों के जब व्यावसायिक बहिष्कार के जेहाद का ऐलान किया था, तो उन्हें यह आशा नहीं थी कि वह बर्रे के छत्ते को छेड़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह उन्हें आशा थी कि महाराष्ट्र के सारे सिख उनके हुकुमनामे का पालन करते हुए खालिस्तान विरोध का नारा लगाने लगेंगे तथा महाराष्ट्र के सारे गुरुद्वारे और उनके ग्रंथी एक स्वर से आतंकवादियों को 'तनखैया' करार देंगे। लेकिन हुआ एकदम उलटा। न केवल महाराष्ट्र के सिखो के बचाव के लिए अपने सारे जरूरी कामकाज छोड़कर अकाली नेता सुरजीत सिंह बरनाला दौड़े-दौड़े बंबई आ पहुंचे, बल्कि बाल ठाकरे को मात देने का सही

मौका जानकर कांग्रेसी महकमा और दूसरे दल भी आगे आ खड़े हुए। महाराष्ट्र के परेशानहाल व्यवसायी सिख बाल ठाकरे के ऐलान के सामने शायद झुक जाते, लेकिन अपना साथ देने के लिए आये राजनीतिक हिमायतियों के तबके ने सिखों के एक तबके को आत्मबल तो दिया, लेकिन आम सिख समुदाय फिर भी आतंकित रहा। इसीलिए बरनाला की बंबई-यात्रा के दौरान भी वह उनसे कटा-कटा रहा। उसे न तो इन राजनीतिक वादों पर भरोसा था और न ही मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण के बाल ठाकरे-विरोधी बयानों एवं सुरक्षा की गारंटी के आश्वासनों पर।

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त थल सेनाध्यक्ष जनरल अरुण वैद्य की दिनदहाड़े आतंकवादियों द्वारा की गयी हत्या के बाद भी माहौल उतना गर्म नहीं हुआ था, जितना बाल ठाकरे की इस आर्थिक बहिष्कार की धमकी से हुआ है। १९८४ में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या की प्रतिक्रियास्वरूप जब देश का अधिकांश हिस्सा तनावों की आग में जल रहा था, तब सिर्फ बंबई के सिख अपने को महफूज पा रहे थे और तब श्री ठाकरे पर आरोप लगा था कि उन्होंने यहां के सिख समुदाय से एक 'सौदा' कर अपने सारे शिवसैनिक उनकी तथा उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिये थे। श्री ठाकरे इस तथाकथित 'सौदे' से इनकार करते हुए कहते हैं कि उस समय जब कांग्रेसी हुकूमत में सारा देश जल रहा था, उनका नैतिक कर्तव्य था कि वह 'आमची महाराष्ट्र' में रह रहे सिखों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते। ऐसे में उनके इस अप्रत्याशित आर्थिक बहिष्कार की धमकी की क्या जरूरत पड़ गयी और उन्हें महाराष्ट्र के सिखों की नेकनीयती पर संदेह कैसे हो गया?

ठाकरे का शक: श्री ठाकरे ने यह चेतावनी तब दी, जब पंजाब में शिवसेना-प्रमुख जगदीश टांगड़ी ने बंबई आकर उनसे मुलाकात की और पंजाब में निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की अपील की। पंजाब में दिनोंदिन बढ़ रही हिंदुओं की हत्याओं तथा उन्हें न रोक पाने की सरकारी-तंत्र की असफलताओं के कारण बाल ठाकरे शुरू से ही क्षुब्ध थे और वह अपनी नाराजगी का इजहार भी कई मौकों पर कर चुके थे। पंजाब में शिवसेना का गठन इसी इजहार का एक परिणाम था।

जगदीश टांगड़ी की अपील से प्रभावित हो बाल ठाकरे ने उनके साथ एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन का आयोजन कर चेतावनी दी कि यदि निरपराध व्यक्तियों की हत्या करनेवाले उग्रवादियों को 'तनखैया' घोषित नहीं किया गया और १५ दिन के भीतर हिंसा नहीं रुकी, तो सिखों से आर्थिक संबंध तोड़ लिये जायेंगे। जिन टैक्सियों, होटलों या दूकानों को सिख चलाते हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जायेगा। श्री ठाकरे को विश्वास था कि उग्रपंथियों को आर्थिक सहायता का एक बड़ा हिस्सा बंबई के सिख व्यापारियों से मिलता है और जब वे भागकर बंबई आते हैं, तो उन्हें शरण भी मिलती है।

श्री ठाकरे का शक बेबुनियाद नहीं था। पंजाब और दिल्ली में गिरफ्तार कई आतंकवादियों ने पुलिस के सामने मंजूर किया था कि वे बंबई के विभिन्न गुरुद्वारों में रुके थे और उन्होंने बंबई से काफी कोष इकट्ठा किया था। १९८० में भिडरांवाले ने बंबई आकर काफी चंदा एकत्र किया था। जनरल वैद्य की हत्या करने के पहले जिंदा एंटाप हिल स्थित सरकारी कर्मचारियों के एक फ्लैट को किराये पर लेकर दो दिन तक रुका रहा। जलगांव में एक ट्रक में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी।

लेकिन ये ऐसे कारण नही थे कि बाल ठाकरे को इतना गंभीर कदम उठाने की जरूरत पड़ती, जिससे सिखों की देशभक्ति निष्ठा पर शक किया जाता अथवा उन्हें अपनी निष्ठा का सबूत देने की जरूरत पड़ती। इसके बावजूद बंबई के सिख संगठनों ने श्री ठाकरे से मुलाकात की और उनके कहे मुताबिक एक बार फिर भारत के प्रति निष्ठा व्यक्त की।

श्री ठाकरे ने आर्थिक बहिष्कार को एक महीना और टालने का निर्णय देते हुए बंबई के सिखों को यह प्रमाणित करने के लिए ३० दिन की मोहलत दी कि वे न केवल खालिस्तान विरोधी हैं बल्कि उन्हें 'तनखैया' घोषित करने के लिए वे ग्रंथियों से अपील करेंगे। श्री ठाकरे दर्शन सिंह जैसे ग्रंथियों की गतिविधियों की भर्त्सना करते हैं और ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला आदि को प्रमुख ग्रंथियों द्वारा द्री गयी सजा का विरोध करते हैं और वह चाहते हैं कि ऐसा बंबई के सिख भी करें।

बाल ठाकरे चाहते थे कि सिख नेता सार्वजनिक रूप से अपनी बात घोषित करें, इसके लिए उन्होंने एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी शर्तें दोहराते हुए उनके सामने दस सवाल रखे और एक महीने की मोहलत देते हुए कहा कि इन सवालों के जवाब देने के बाद ही बहिष्कार खतम होगा।

सिखों की प्रतिक्रिया: २१ मार्च को गुरुसिंह सभा बंबई ने अकाल तख्त के जत्थेदार भाई जसबीर सिंह रोड़े से अपील की कि वह अकाल तख्त के सिद्धांतों की खातिर हुक्मनामा जारी करें ताकि निर्दोषों की हत्या बंद हो सके। सभा के एक पदाधिकारी तथा महाराष्ट्र के ३५ सिख संगठनों से संबद्ध प्रमुख सिख नेता कुलदीप सिंह चड्ढा ने श्री ठाकरे को एक पत्र लिखकर अमृतसर जानेवाले प्रस्तावित शिष्टमंडल में शामिल होने का अनुरोध किया। यह पूछे जाने पर कि अगर उनके साथ श्री ठाकरे नहीं जाते तो वे क्या करेंगे, उन्होंने तुर्की-ब-तुर्की कहा, "ऐसे में हम उनके कहन पर या किसी के दबाव में आकर नहीं जायेंगे। अगर वे हमारा आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तो हम यहीं रहकर स्थिति का मुकाबला करेंगे।"

नांदेड गुरुद्वारा के ज्ञानी गुरवचन सिंह ने बतलाया कि हम श्री ठाकरे के घर बातचीत के लिए इसलिए नहीं गये थे कि हम डर गये थे। हमने उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया कि इस बहिष्कार के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं और इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है।

> **पंजाब को तोड़ने की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है। इस बात पर उन्हें (श्री ठाकरे) यह सोचना चाहिए कि अगर उनका दुस्साहस सीमा पार कर गया, तो इच्छा न होते हुई भी हमें (उनके विरुद्ध) कड़ा कदम उठाना ही होगा।**
>
> *—शंकर राव चह्वाण*

गुरुसिंह सभा के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह कोहली का कहना था कि उनके (बाल ठाकरे) आमंत्रण पर हम १६ मार्च को उनके घर गये। उन्होंने कहा, "आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? पंजाब में रोजाना इतनी हत्याएं हो रही हैं और आप बंबई से हत्यारे आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। एक करोड़ रुपए रोज वहां भेजा जा रहा है। अकेले आपेरा हाउस (इस क्षेत्र में सिखों के बिजली तथा मोटर पार्ट्स की तमाम दूकानें हैं) से ही एक लाख रुपए प्रतिदिन भेजा जा रहा है।" हमने उन्हें बतलाया कि ये सारी खबरें झूठी हैं। हम न तो खालिस्तान की मांग के समर्थक हैं, न ही आतंकवादियों के मददगार।

बंबई कांग्रेस अध्यक्ष मुरली देवडा का कहना

था, "सिख नेताओं को उनसे (बाल ठाकरे) बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पूरे सिख समुदाय को दोषी ठहरा कर उसे धमकी देना 'ब्लैक मेल' करने के समान है।"

सिख नेताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन अलग से आयोजित कर अपने मंतव्य की सूचना दी। इस पर श्री ठाकरे ने २२ मार्च को एक अलग प्रेस सम्मेलन में कहा, "बंबई के सिख पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं रोकने के उनके संयुक्त प्रयास की अपील मानने की बजाय टकराव का रास्ता अपना रहे हैं। मैंने पूरे सिख समुदाय को कभी भी राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा। उनके त्याग और शूरवीरता की स्वर्णिम गाथा है और मैं इसका प्रशंसक हूं। संप्रति असली मुद्दा है, पंजाब के बाहर रहनेवाले सिख पंजाब में रोजाना हो रही नृशंस हत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं।"

श्री बरनाला के अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस के एक नेता एमएमएस चीमा तथा बहुत से दूसरे नेता भी इस टकराव को टालने के लिए बंबई आये, लेकिन उनकी आमदरफ्त सिख समुदाय और गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री तक ही रही। इनमें से किसी ने बाल ठाकरे से मिलकर मामले को शांतिपूर्वक निपटाने की जरूरत महसूस नहीं की।

पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला चिंतित होकर बंबई आये और मुख्यमंत्री चह्वाण से मिले। श्री बरनाला ने बताया, "मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी सिख परिवार को महाराष्ट्र छोड़ने की जरूरत नहीं है।" मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

—सुरजीत सिंह बरनाला

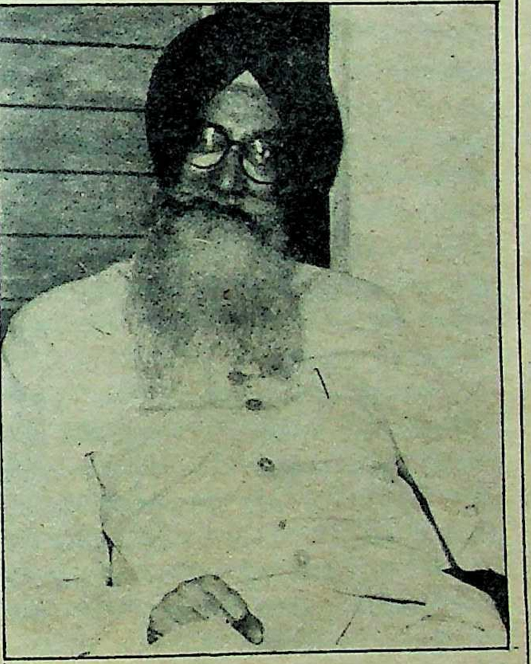

राज्य-सरकार का रुख: अपने निर्णय पर अडिग बाल ठाकरे ने चतुर्दिक बढ़ते विरोध को देखते हुए एक महीने तक के लिए चुप्पी साध ली और किसी भी पत्रकार से बातचीत करने या कोई वक्तव्य देने पर पाबंदी लगा दी। महाराष्ट्र विधानसभा में २४ मार्च को सिखों के बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण सूचना लगी, परंतु विधानसभा अध्यक्ष शंकर राव जगताप ने बतलाया कि सरकार ने उत्तर देने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस विधायक बलवंत देसाई अध्यक्ष आसन के नीचे पहुंच गये। उनकी पार्टी के मदन बाफना, शरद रणदिवे आदि विधायक चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाये और सरकार शिवसेना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण ने उन्हें सूचना दी कि कानून विशेषज्ञ की राय के बाद ही वह सरकारी कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे।

२६ मार्च को मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया, "गत ५ एवं १६ मार्च को हुए पत्रकार सम्मेलनों में सांप्रदायिक विद्वेष की भावना भड़काने के आरोप में नगर पुलिस ने बाल ठाकरे के विरुद्ध दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि धमकी वापस न लेने पर उनके विरुद्ध सरकार उचित कार्रवाई करेगी। ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। यदि उनकी धमकी के भय से एक भी सिख अल्पसंख्यक को राज्य छोड़ना पड़ा, तो यह प्रशासन की हार मानी जायेगी। उनकी (बाल ठाकरे) यह चेतावनी कि 'हाथ लगाया, तो राज्य सुलग उठेगा' मेरे मन में नाराजगी पैदा करने के लिए पर्याप्त है। सिखों के आर्थिक बहिष्कार करने का अधिकार दिया किसने उन्हें? क्या उन्हें पता है कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम के क्या प्रावधान हैं? पंजाब को तोड़ने की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है। इस बात पर उन्हें (श्री ठाकरे) यह सोचना चाहिए कि अगर उनका दुस्साहस सीमा पार कर गया, तो इच्छा न होते हुए भी हमें (उनके विरुद्ध) कड़ा कदम उठाना ही होगा।"

श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने मुख्यमंत्री के उक्त वक्तव्य की चर्चा करते हुए 'माया' को बतलाया, "उनका यह वक्तव्य काफी बोल्ड था और यहां रहनेवाले सिखों को विश्वास दिलाने के लिए काफी पर्याप्त। इतना 'बोल्ड स्टेटमेंट' तो बहुत चाहते हुए मैं भी कभी नहीं दे पाया था।"

ठाकरे की प्रतिक्रिया: मुख्यमंत्री श्री चह्वाण का बाल ठाकरे-विरोध जगज़ाहिर है, इसलिए बहुत से शिवसेना नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री की 'ठाकरे विरोधी भड़ास' की संज्ञा दी। बाल ठाकरे ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, "जब दिल्ली में १९८४ में कत्लेआम हो रहा था तब उन्होंने (श्री चह्वाण केंद्रीय मंत्री थे) सिखों को कितना संरक्षण दिया था, भला जो आज उनके हमदर्द बनने का दावा करने लगे हैं!"

श्री ठाकरे ने एक महीने के मौनव्रत के बावजूद अपने अखबार 'मार्मिक' में (जिसके वह संपादक भी हैं) लिखा, "मुट्ठी भर सिखों के आर्थिक बहिष्कार से आतंकवादी चुप नहीं बैठेंगे, इतनी अक्ल हमें है। किंतु दबाव डालने के सिवा और कोई चारा नहीं।"

श्री ठाकरे की चुप्पी के बावजूद उनके समर्थक मुखर एवं बहिष्कार की धमकी पर अडिग हैं। शिवसेना में ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के नेता मनोहर जोशी ने 'माया' को बतलाया, "हमने किसी सिख को परेशान या आतंकित करने का इरादा नहीं किया। सिखों की दूकानों या होटलों पर जाकर हमारे कार्यकर्ता हाथ जोड़कर ग्राहकों से विनती करेंगे, ताकि वे बहिष्कार में शामिल हों।"

बंबई के भूतपूर्व महापौर तथा विधायक छगन भुजबल की भाषा ज्यादा उग्र है। उनका कहना है, "बहिष्कार का फैसला सही है। जो लोग शिवसेना या बाला साहेब (ठाकरे) को फासिस्ट कहते हैं, उन्हें अपने नेताओं तथा पार्टी के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। सिख आतंकवाद अब सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने जनरल अरुण वैद्य की हत्या कर दी। बंबई के अनेक सिख आतंकवादियों को चंदा और पनाह देते हैं। १९८० में खुद जरनैल सिंह भिंडरांवाले बंबई से चंदा वसूल कर गये थे। पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा सकी।"

भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता दत्ता पाटील समेत अनेक नेता यह मानकर चलें कि श्री ठाकरे ने दूरगामी नतीजों को समझे बगैर जल्दबाजी में धमकी दे डाली, परंतु राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा नहीं मानते। उनकी राय में बंबई के एक लाख सिखों में ज्यादातर व्यापारी हैं। बंबई का ९० प्रतिशत मोटर पार्ट का धंधा उनके हाथों में है, जबकि ६५ प्रतिशत ट्रक-व्यवसाय पर उनका कब्जा है। एक ओर तो धमकी से एकाधिकार टूटेगा, जिसके लिए अंदर-ही-अंदर कई साल से कोशिश जारी है और दूसरी ओर उनसे कांग्रेस को मिलनेवाला चंदा कम हो जायेगा।

बहरहाल, बहिष्कार की धमकी से आतंकवादी खुश हैं, और खुले आम कह रहे हैं कि 'हिंदू राज' में ऐसा ही होना है। पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला चिंतित होकर बंबई आये और मुख्यमंत्री चह्वाण से मिले। श्री बरनाला ने बताया, "मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी सिख परिवार को महाराष्ट्र छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।" देखना यही है कि शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस सरकार प्रचारात्मक कार्रवाई करती है या सचमुच मुकदमा चलाती है। यों कांग्रेस का संगठन इतना लुंजपुंज है कि शिवसेना को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

—बंबई ब्यूरो

विधायक बनाम पुलिस अफसर

हरिजन लड़की की जिंदगी से खिलवाड़

पहली अप्रैल को राजस्थान विधानसभा में लोकदल-ब विधायक जगमाल सिंह यादव पर लगे बलात्कार के आरोप के मामले ने उस समय दिलचस्प मोड़ ले लिया, जब पक्ष-विपक्ष के प्रायः सभी सदस्यों ने इसे एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिंह का विधायक के खिलाफ षड्यंत्र बताया और सरकार ने एक जांच समिति गठित करने की घोषणा की। यह मामला एक नाबालिग़ हरिजन लड़की केसर के साथ हुए बलात्कार से संबंधित है। क्या एक हरिजन लड़की के भविष्य की क्रूर उपेक्षा करते हुए, उसको राजनीतिक हथियार बना लिया गया है?

मेरी लड़की को पुलिस से बचाओ : सवाई सिंह भाट

पहली अप्रैल को राजस्थान विधानसभा में ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, जिसमें मंत्रियों को छोड़कर यह अंदाज लगाना मुश्किल हो गया कि कौन विधायक सत्तापक्ष का है और कौन विपक्ष का। मामला लोकदल-ब विधायक जगमाल सिंह को लेकर स्थानीय अखबार में छपी इस खबर से जुड़ा था कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र तिजारा के एक कस्बे टपूकड़ा की रहनेवाली एक हरिजन लड़की से बलात्कार किया। मजे की बात यह है कि पक्ष-विपक्ष के विधायक जगमाल सिंह को दोषी नहीं मान रहे थे, बल्कि उनका आक्रोश उस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिंह के विरुद्ध था जो इस बलात्कार कांड की जांच कर रहे थे। विधायकों का आरोप था कि इसी पुलिस अफसर ने षड्यंत्र रचकर उक्त विधायक को इस बलात्कार कांड में फंसाया है तथा वास्तविक अपराधियों को ८५ हजार रुपए की घूस लेकर छोड़ दिया है। सदस्य इतने उत्तेजित थे कि विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी को प्रश्न काल स्थगित करने के साथ सदन की कार्यवाहीं तीन घंटे रोकनी पड़ी। सदस्य हायतौबा मचा रहे थे कि सदन की कार्यवाही यदि नहीं चल रही होती, तो जगमाल सिंह को हथकड़ी डालकर सारे बाजारों में घुमाया जाता और विधानसभा की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती। जो विधान सभा कुछ अर्सा पहले कांग्रेस-इ विधायक डा० राजकुमार जयमाल पर स्वाति लोधा से बलात्कार करने के लगे आरोप पर मौन थी, उसने एक प्रकार से जगमाल सिंह यादव को बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया था। स्वयं मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिंह और सबंधित थानेदानर का तबादला करने की तत्काल घोषणा की और जगमाल सिंह यादव के खिलाफ षड्यंत्र करनेवाले पुलिस अफसरों की जांच के लिए पक्ष-विपक्ष के पांच विधायकों की समिति बनाने का ऐलान भी कर दिया। रोचक तथ्य यह है कि विधायकों को एक विधायक पर बलात्कार का आरोप लगने से पूरी विधानसभा की प्रतिष्ठा धूलधूसर होती नजर आ रही थी, लेकिन उस गरीब नाबालिग हरिजन लड़की केसर के प्रति किसी को कोई संवेदना नहीं थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ था। पूरे घटनाचक्र को देखने से सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक विधायक और एक पुलिस अफसर अपने-अपने जातीय स्वार्थों से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक बेबस हरिजन लड़की को मोहरा बनाकर खेल रहे हैं?

घटनाक्रम: नाबालिग हरिजन लड़की केसरबाई से हुए बलात्कार की कहानी तीन मोड़ लेती है। दिनांक २ फरवरी, १९८८ को अपने पिता सवाई सिंह भाट के साथ थाना पूकड़ा पहुंचकर केसरबाई ने जो रिपोर्ट लिखाई उसके अनुसार एक फरवरी, १९८८ को सायंकाल पौने सात से आठ बजे के बीच आशाराम की शह पर सलेम, रघुवीर और कंवर सिंह ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। पुलिस ने मुकदमा नंबर १२/१८ के तहत भादंस की धाराओं ३६३/३६६/१२०-बी के अंतर्गत प्रकरण कायम कर लिया। ये लोग शराब के ठेकेदारों के आदमी बताये जाते हैं। इस घटना की सूचना जब इस क्षेत्र के विधायक जगमाल सिंह यादव को मिली, तो उन्होंने केसर का एक और बयान धारा २०२ के तहत दर्ज करवाया—इसके अनुसार पहली रिपोर्ट के बाकी सब तथ्य तो ज्यों-के-त्यों रहे, लेकिन बलात्कार करनेवालों में से कंवर सिंह यादव का नाम हटाकर सरदा मेव का नाम जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि जगमाल सिंह यादव ने अपने जात भाई कंवर सिंह यादव को बचाने के लिए रिपोर्ट बदलवायी थी। इस बीच भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग में सबंधित अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जयपुर स्थित निदेशक रमेश चंद मीणा जब टपूकड़ा जाकर केसर से मिले, तो उस समय भी केसर ने वही बातें बतायी जो उसने धारा २०२ में दर्ज करवायी थीं। कहा जाता है कि श्री मीणा ने इस मामले से कंवर सिंह का नाम हटाये जाने पर खासा एतराज किया था।

अगले दिन केसर के ये बयान जब अखबारों में छपे, तो विधायक जगमाल सिंह स्तब्ध रह गये।

इस कहानी ने दूसरा मोड़ उस वक्त लिया जब स्वयं विधायक जगमाल सिंह ने एक मार्च को विधानसभा में बलात्कार का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इस जघन्य कांड में शराब के दो ठेकेदार और टपूकड़ा ब्लाक कांग्रेस-इ का उपाध्यक्ष रघुबीर महाजन शामिल है तथा इस घटना की जांच करनेवाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिंह रुपए खाकर असली मुल्जिमों को बचा रहे हैं। जगमाल सिंह के इस आरोप से टपूकड़ा में केसर के लिए नयी मुसीबतें शुरू हो गयीं। कहा जाता है कि पुलिस और शराब के ठेकेदार केसर को अपना बयान बदलवाने के लिए धमकियां और लालच देने लगे। लेकिन इन सबका केसर पर कोई असर नहीं पड़ा, तो २६ मार्च, १९८८ को केसर का अपहरण हो जाता है। उसके पिता सवाई सिंह ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवायी कि सलेम, सरदा मेव व ओमप्रकाश गुप्ता मुझे केसर के बयान बदलवाने के लिए बार-बार धमकियां और लालच दे रहे थे। उसने इस अपहरण का आरोप शराब के एक ठेकेदार के आदमी रैवती हैदरा, सलेम, ओम प्रकाश गुप्ता और सरदा मेव पर लगाते हुए यह शक भी जाहिर किया कि इस अपहरण में अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिंह का हाथ भी हो सकता है।

तीसरा मोड़: 'बलात्कार कांड' की सारी कहानी ३० मार्च को तीसरा मोड़ ले लेती है। पुलिस ने केसर को इसनाका नांगल ग्राम से बरामद कर ३० मार्च को अलवर के अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दंडनायक के सामने प्रस्तुत किया, जहां धारा-१६४ के तहत उसने जो बयान दर्ज कराया, उसमें सारी कहानी ही बदल गयी। उसने अपने बयान में कहा कि उसने पहले बलात्कार की जो रिपोर्ट दर्ज करायी थी वह झूठी थी और विधायक जगमाल सिह यादव के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट लिखायी थी। उसने यह भी कहा कि २६ मार्च को उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह स्वयं अपने पिता सवाई सिह से पीछा छुड़ाकर अपनी बुआ के यहां चली गयी थी, क्योंकि उसका पिता उससे पेशा कराना और उसे बेच देना चाहता था। केसर ने अपने बयान में यह भी बताया कि उस दिन उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, बल्कि अपने पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक आदमी भेजकर खुद अनिल यादव को बुलवाया तथा उससे बात करने के बाद वह सरदा मेव से बात करने लगी थी। रात बहुत हो जाने के कारण वह अपनी बुआ रेवती के घर चली गयी। सुबह उसका पिता दो सिपाहियों को साथ लेकर वहां पहुंचा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे अपने माथ ले गया तथा दबाव में आकर उसने सामूहिक बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट लिखाने के बाद विधायक जगमाल सिह की भूमिका शुरू होती है। कंवर सिह का नाम रिपोर्ट से निकलवाने के कुछ दिनों बाद केसर के बयान के अनुसार जगमाल सिह यादव ने एक आदमी भेजकर उसके पिता और उसे जयपुर बुलवा लिया। यहां वह उसके पिता को शराब पिलाकर बाहर भेज देता और उसके साथ बलात्कार करता। तीन दिनों तक उसके साथ बलात्कार हुआ, जिससे वह १४ दिन बीमार पड़ी रही। बीमार होने के कारण विधायक ने उसे तथा उसके पिता को वापस टपूकड़ा भेज दिया। उसके बाद भी विधायक ने उसे कई बार जयपुर बुलवाया, लेकिन वह नहीं गयी। अदालत में केसर ने यह भी कहा कि उसे उसकी बुआ के पास भेज दिया जाये जो उसकी जिंदगी सुधारकर उसे बुरे धंधे से बचाना चाहती है।

अगले दिन केसर के ये बयान जब अखबारों में छपे, तो विधायक जगमाल सिह स्तब्ध रह गये। कहा जाता है कि वह बलात्कार के मामले में अपने जातभाई कंवर सिह यादव को बचाने के लिए केसर से धारा-२०२ के तहत बयान दिलवाकर संतुष्ट थे कि अब शराब के ठेकेदारों और पुलिस अफसरों को छठी का दूध याद आ जायेगा, लेकिन सारा पासा पलट गया।

फिलहाल, यह कथा लिखने तक किसी को पता नहीं है कि केसर को पुलिस ने कहां रखा हुआ है। कुछ विपक्षी नेता और पत्रकार भी केसर से मिलना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि केसर भरतपुर में है। इस पूरे मामले का एक रोचक पक्ष यह है कि पुलिस केसर को बालिग मानती है जबकि केसर के पिता और विधायक जगमाल सिह केसर को छठी कक्षा में पढ़नेवाली ११-१२ वर्षीय लड़की मानते हैं, जिसकी जन्म तिथि ७ जुलाई, १९७६ स्कूल में दर्ज है। लेकिन डाक्टरी जांच उसके शरीर को सत्रह वर्षीय युवती की तरह विकसित मानती है। जगमाल सिह ने 'माया' को बताया, "अदालत में दिये बयानों को अगर आप पढ़ें, तो आप कानून के ज्ञाता न होते हुए भी उसका अर्थ समझ जायेंगे। बारह साल की लड़की ऐसे बयान नहीं दे सकती जो पुलिस ने नियोजित तरीके से उससे दिलवाये हैं। इन बयानों से एडिशनल एसपी केके सिह का मकसद तो पूरा हो ही गया।"

महेंद्र शास्त्री

जब सारा सदन लोकदल-ब विधायक जगमाल सिंह की तरफदारी कर रहा था, तब महेन्द्र शास्त्री मौन थे।

केके सिह कौन हैं?: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिह जाट होने के साथ-साथ वर्तमान पुलिस महानिदेशक ज्ञान प्रकाश पिलानिया के रिश्तेदार बताये जाते हैं। भाजपा विधायक नाथू सिह ने विधानसभा में केके सिह का जो इतिहास बताया उससे विधायक जगमाल सिह का ही पक्ष मजबूत हो गया। नाथू सिह के अनुसार, "१९६५ में केके सिह अजमेर संभाग के ब्यावर में डीएसपी की हैसियत से नियुक्त थे। यहा नियुक्त रहते हुए उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ एक महिला चिकित्सक से बलात्कार किया था। तत्कालीन अजमेर एसपी भंवर गोविंद सिह ने मामले की जांच की थी। इसी जांच के आधार पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में १९६७ में प्रदेश में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस दौरान इन्हें पुनः बहाल किया गया, लेकिन जैसे ही निर्वाचित सरकार बनी, इन्हें पुनः निलंबित कर दिया गया।" नाथू सिह का कहना था कि केके सिह फिर सेवा में कैसे आये, यह अभी रहस्य है। इस प्रकार बदनाम पृष्ठभूमि और पुलिस की बदनाम छवि केके सिह को संदेह के घेरे में ले आती है, वहीं केसर का पिता सवाई सिह भाट भी रहस्यमय नजर आता है। केसर के बदले बयान जहां अपने पिता पर ही उससे पेशा कराने के लिए दबाव डालने का तथा विधायक जगमाल सिह पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर केसर का पिता विधायक जगमाल सिह को देवता मानता है। उसके अनुसार, "अपने जिस्म की चमड़ी के जूते भी बनाकर इन्हें पहना दूं, तो इनका अहसान नहीं उतरेगा।" केसर के बदले बयानों के संबंध में उसका कहना है, "मुझे पता लगा है कि एडिशनल एसपी ने उसे मार-मार कर बयान देने को तैयार किया है। अलवर के सदर थाने में लड़की को कंबल बिछाकर उलटा पटका है, फिर कंबल से ढककर मारा है। उसे बिजली के करंट लगाने की हरकतें की हैं, तब लड़की ने घबराकर यह सब बोला है जो एडिशनल एसपी साहब चाहते हैं।"

केके सिह जाट होने के साथ-साथ वर्तमान पुलिस महानिदेशक ज्ञान प्रकाश पिलानिया के रिश्तेदार बताये जाते हैं।

सवाल उठता है कि कौन झूठ बोल रहा है, केसर या उसका पिता? यदि सवाई सिह भाट को अपनी लड़की से पेशा ही करवाना था, तो उसे स्कूल में दाखिल करवाने की क्या जरूरत थी? यदि केसर सच बोल रही है, तो पुलिस उसे उसके पिता, राजनेताओं और पत्रकारों से मिलने क्यों नहीं दे रही? जगमाल सिह यादव पहली बलात्कार रिपोर्ट से कंवर सिह यादव का नाम क्यों निकलवाना चाहते थे? क्या वास्तव में पुलिस अफसर केके सिह ने घूस खाकर असली अभियुक्तों को निकल जाने दिया और जाति-विद्वेष के कारण उन्होंने केसर के माध्यम से जगमाल सिह यादव को फंसाने के लिए वाकई कोई षड्यंत्र रचा है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए तो पूरी विधानसभा सक्रिय हो गयी है, लेकिन विडंबना यह है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के हितों के प्रति समर्पित राजस्थान सरकार और पक्ष-विपक्ष के नेता हरिजन लड़की केसर के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ से बेखबर बने रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान में राजनीति और पुलिस प्रशासन जातिवादी शिकंजे में इस कदर कसा हुआ है कि सब अपने जात-भाई को बचाने और उसे ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील दिखायी देते हैं। जब सारा सदन लोकदल-ब विधायक जगमाल सिह की तरफदारी कर रहा था, तब उन्हीं के दल और जिले के वरिष्ठ विधायक महेंद्र शास्त्री मौन थे। कहा जाता है कि श्री शास्त्री प्रदेश की जाट राजनीति के नेता हैं, इसी कारण अपनी जात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केके सिह के विरुद्ध जगमाल सिह यादव का खड़ा होना वह पसंद नहीं करते। और-तो-और इसी जातिवाद के चलते पुलिस अफसर केके सिह के कथित षड्यंत्र की जांच के लिए गठित होनेवाली समिति का गठन भी खटाई में पड़ गया है। आरोप है कि जाट पुलिस अफसर केके सिह को बचाने के लिए लोकदल नेता नाथूराम मिर्धा ने जिस लाल चंद डूडी का नाम जांच समिति के लिए प्रस्तावित किया था, उसका लोकदल के युवा विधायकों ने विरोध किया है। ये पंक्तियां लिखे जाने तक जांच समिति गठित नहीं हो पायी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अपनी-अपनी जाति की तो सबको फिकर है, लेकिन केसर के भविष्य की किसी को चिंता नहीं है।

—ओम सैनी

स्कॉटडेल, युएसए निवासी श्रीमती केथलीन ब्लेकबर्न
बंदर छाप काले दंतमंजन की ही
सिफ़ारिश क्यों करती हैं?

"आपको यह बतानेके लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ कि
आपका उत्पादन बंदर छाप काला दंतमंजन इस्तेमाल करनेमें मुझे कितना आनंद मिलता है.
दंतमंजन बेशक उत्तम श्रेणीका है और इसके गुण भी लाजवाब हैं.
मैं बड़ी खुशीके साथ अपने स्नेहीयों से इस दंतमंजनकी सिफारिश करती हूँ...."

(श्रीमती ब्लेकबर्न के पत्रसे)

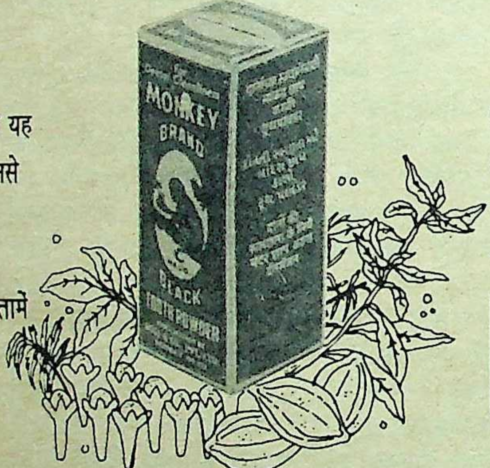

देश और विदेशमें हमारे लाखों ग्राहकों में से यह केवल एक उदाहरण है, जो हमारे उत्पादनसे संतुष्ट है. क्यों?

इसका कारण यह है कि नोगीमें,हम गुणवत्तामें अपार विश्वास रखते है और बाकी सब अपने ग्राहकोंकी, सुझ-बुझपर छोड़ देते है, जैसे श्रीमती ब्लेकबर्न तथा अन्य...

और बंदर छाप काले दंतमंजन की इस कामयाबी का राज़ छुपा है इसके **आयुर्वेदिक फार्मुलेमें. मेन्थॉल, थाइमॉल,** (विशेष रूप से फ्रान्स से आयात किया हुआ), **लौंग तेल** तथा अन्य जड़ी-बूटियों की नपी-तुली मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है. इसे विशिष्ट कालावधि तक परिपक्व होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे परिपूर्ण सुगंध पैदा होती है. इस दंतमंजन में शामिल हर एक तत्त्व की दंतचिकित्सा में अपनी विशेष महत्ता है. थाइमॉल एक जन्तुनाशक तत्त्व है जो मसूड़ोंके लिए गुणकारी है: लौंग का तेल दांतों के दर्द से राहत दिलानेके लिए सुप्रसिध्द है और मेन्थॉल ठंडे स्वादवाला एक कोमल दर्दनिवारक है.

यही नहीं, इसमें हरडा के अतिरिक्त गुण भी शामिल है जो मसूड़ोंको जकड़नेमें मदद करती है और छालोंसे आराम पहुँचाती है. अंतमें, सबसे महत्त्वपूर्ण है इसका कोयला का आधार, जो बंदर छाप काले दंतमंजन को लोकप्रिय बनाता है - दांतोंको चमकदार और सफेद बनानेमें वचनबद्ध है.

इसका कारण यह है कि कोयला दुर्गंधका नाश करता है और दातों को सफ़ेद बनाता है. इसीलिए बंदर छाप काला दंतमंजन आपके दांतोंको ज्यादा साफ और ज्यादा सफ़ेद रखता है.

तो फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि ७५ वर्षोंसे बंदर छाप काला दंतमंजन न केवल भारतमें बल्कि दुनियाभरमें प्रेमपूर्वक अपनाया गया है. क्योंकि श्रीमती ब्लेकबर्न की तरह अधिकतर लोग अपने दातोंकी सही देखभाल के लिए किसी और दंतमंजनपर भरोसा नहीं करते.

बंदर छाप
काला दंतमंजन
७५ वर्षों से
दुनियाभरमें विश्वसनीय

नोगी

सन १९११ से

अब बारी वोरा की !

कभी मोतीलाल वोरा की नाक में दिल्ली में बैठे अर्जुन सिंह दम किया करते थे, लेकिन अब वोरा ने दिल्ली पहुंच कर अर्जुन सिंह के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। वोरा का साथ दे रहे हैं, माधव राव सिंधिया। यह राजनीतिक खेल क्यों और कैसे चल रहा है ?

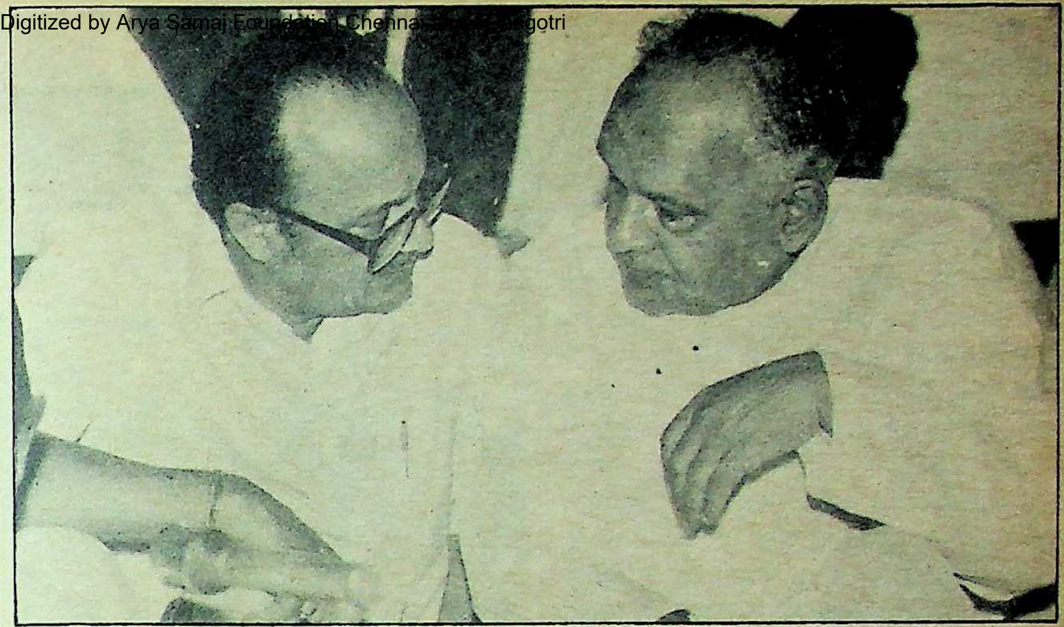

रणनीति में मशगूल: अर्जुन सिंह और चंदूलाल चंद्राकर

वोरा को हरी झंडी: माधव राव सिंधिया

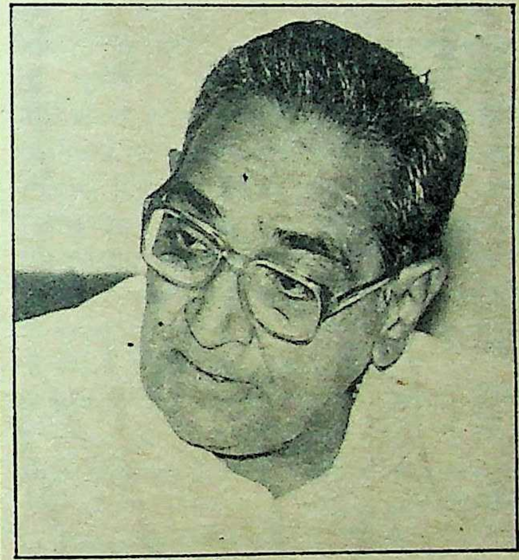

बदला: मोतीलाल वोरा

अर्जुन सिंह को आलाकमान की मरजी से मध्य प्रदेश में आये एक तिमाही भी नहीं बीती है, मगर सत्तारूढ़ दल के खेमे में असंतोष सुगबुगाने लगा है। मजे की बात यह है कि इस असंतोष को दिल्ली के ही कुछ नेता हवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुनसिंह हवा के इस रुख को भांप नहीं रहे हैं। खिलाफत में सक्रिय खेमे में हो रही हलचल की जानकारी का ही यह नतीजा है कि ताबड़तोड़ फैसलों के बजाय उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता काम करने का मन बना लिया है।

सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए सर्वाधिक हैरत की बात यह है कि बीते कल के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के तेवर इन दिनों बदले हुए हैं। अब यह बात लुकी छिपी नहीं रही है कि वोरा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि गुटों की गोटियां न खेलने की राजनीति के एवज में आलाकमान उन्हें पद पर बिठाये रखेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की भांति पद से हटाये जाने का निर्णय भी उनके लिए विस्मयकारी रहा। दिल्ली से बूटा सिंह के निर्देश के बाद भी तत्काल इस्तीफा न देना, केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया को खबर करना और सिंधिया का दौरा अधूरा छोड़कर दिल्ली जाने का घटनाक्रम वोरा की तत्कालीन मनःस्थिति और उन्हें बचाने में आकाओं की विफलता को रेखांकित करता है। केंद्र सरकार में मंत्रिपद मिलने से उनके घावों पर मलहम तो लगा, लेकिन वह क्षोभ शांत नहीं हुआ जो उनकी नजरों में 'अकारण और तुरतफुरत विदाई' से उपजा था।

शंखनाद: दो केंद्रीय मंत्रियों—माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा के २६ मार्च के मध्य प्रदेश के दौरे को फिलहाल उपरोक्त संदर्भों में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि असंतुष्ट धड़ा इन दोनों नेताओं की अगुवाई में एकजुट होकर अर्जुन सिंह के खिलाफ कमर कस रहा है। दतिया, ओरछा और पन्ना के दौरे में शामिल नेताओं के नामों और उनके भाषण पर गौर करें, तो उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। दौरे में शुरू से लेकर अंत तक शरीक रहे एक महत्वपूर्ण नेता के अनुसार काबिलेगौर बात यह है कि हमने कुंवर साहब के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद रामनवमी के दिन किया है। विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई को धर्मयुद्ध की संज्ञा देते उन्होंने महाराज सिंधिया के इस आशय के कथन का भी हवाला दिया कि हमें आसुरी प्रवृत्तियों और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ निरंतर संघर्ष करना है। बगैर नामोल्लेख के सिंधिया ने यहां यह भी कहा कि भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध संघर्ष में वह जनता के साथ हैं। पूर्व गृह राज्यमंत्री कैप्टन जयपाल सिंह मंच से यह कामना करने से भी नहीं चूके कि दोनों नेता सिंधिया व वोरा-राज्य के कोने-कोने में इसी तरह अपना रथ-हेलीकाप्टर-उतारें।

बुंदेलखंड के इस दौरे में सिंधिया और वोरा के साथ-साथ अर्जुन विरोधी सांसदों की तिकड़ी दिल्ली से आयी। इस तिकड़ी में सुरेश पचौरी, सुरेंद्र सिंह ठाकुर और दिलीप सिंह भूरिया का समावेश है। सांसद विद्यावती चतुर्वेदी के अलावा प्रदेश के विधिमंत्री बालेंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह, मध्य प्रदेश निर्यात निगम के अध्यक्ष मनोहर बैरागी और दसेक विधायक शरीक हुए। ओरछा, बुधैड़ा, शाहनगर और पवई की सभाओं में 'परस्परं प्रशंसन्ति' का दौर तो चला, लेकिन वोरा समेत किसी भी नेता ने वर्तमान मुख्यमंत्री सिंह का जिक्र नहीं किया। 'माया' सूत्रों के अनुसार इन दिनों सिंधिया के मध्यभारत के आगामी दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है कि झाबुआ, मंदसौर, इंदौर और उज्जैन के दौरों में यह अर्जुन-विरोधी अभियान और परवान चढ़ेगा।

उत्तराधिकार: केंद्रीय स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री मोतीलाल वोरा के बारे में माना जाता है कि वह मौजूदा राजनीति के विकारों से परे हैं और औरों की लीक पर नहीं चलते। इन दिनों जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वोरा जल्द ही इस धारणा को झुठला देंगे। वोरा के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उनकी दुर्ग की परंपरागत सीट खाली हो गयी है और पूरे आसार हैं

कि वोरा यहां से अपने छोटे बेटे अरुण वोरा को विधानसभा के लिए इंका टिकट दिलाने की चेष्टा करेंगे। युवा कांग्रेस में पद पाकर अरुण वोरा राजनीति में कभी के दीक्षित हो चुके हैं और स्थानीय राजनीतिज्ञ उन्हें अभी से वोरा का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने लगे हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अर्जुन सिंह की खिलाफत की मुहीम में लगे मोतीलाल वोरा उत्तराधिकार के मामले में अर्जुन सिंह की लीक पर चलते हैं या नहीं। वैसे यदि वोरा सिंह की लीक पर चलते हैं, तो सिंह उनका इस नाते विरोध नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह स्वयं अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाने का दृष्टांत उपस्थित कर चुके हैं। दुर्ग के राजनीतिज्ञों का कहना है कि अरुण वोरा को चुनाव लड़ने और राजनीति में पांव जमाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पिता समेत एक ताकतवर लाबी का संरक्षण मिलने के अलावा उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा कि जनमोर्चा समेत विरोधी पक्ष के नेताओं के मन में भी उनके पिता के प्रति कोमल भाव है। भोपाल में पैंतालीस बंगले में जनमोर्चा को कार्यालय के लिए सरकारी बंगला आवंटित कर वोरा विद्या भैया का मन जीत चुके हैं। कभी विद्याचरण के खासमखास रहे प्रदेश इंका के महामंत्री मनोहर बैरागी और पूर्व सांसद मैमूना सुल्तान को उपकृत करने का काम भी वोरा बखूबी कर चुके हैं। और कुछ हो या न हो, परंतु इसकी पुष्टि उनके नजदीकी लोग भी करते हैं कि वोरा के तेवर बदले हुए हैं और वह गुटीय राजनीति की गोटियां खेलने के मूड में हैं। देखना यह है कि प्रदेश की राजनीति में वोरा की बढ़ती रुचि क्या गुल खिलाती है ? उधर दिल्ली में वोरा-समर्थक सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलने का क्रम जारी है।

वोरा और वोरा गुट के बदले हुए तेवरों का संकेत बाहर ही नहीं, विधानसभा के भीतर भी मिल चुका है। विधायक सत्यदेव कटारे स्पीकर राजेंद्र शुक्ल से उलझकर यहां तक कह चुके हैं कि विधानसभा आपकी जागीर नहीं है। इसी क्रम में कैप्टन जयपाल सिंह और राजस्व मंत्री राजमणि पटेल में भी सदन में तकरार हो चुकी है और दोनों एक दूसरे की जागरूकता को चुनौती दे चुके हैं। वोरा के काकस के सदस्य पूर्व राज्यमंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी गृह एवं परिवहन मंत्री भारत सिंह से उलझ चुके हैं और प्रायः चुप रहनेवाले पूर्व खाद्य मंत्री डा० कन्हैया लाल शर्मा भी इन दिनों मुखर हैं। कहना चाहिए कि इन दिनों सत्तारूढ़ दल के भीतर शनैः-शनैः विपक्ष उभर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि अर्जुन सिंह शक्तिशाली भले ही हों, निरापद कतई नहीं हैं। भोपाल और दिल्ली-दोनों जगहों पर उनके खिलाफ लाबियां सक्रिय हैं। प्रतिशोध की राजनीति से उनकी धाक भले ही जमे, किंतु इससे असंतुष्टों की तादाद और ताकत दोनों में इजाफा हो रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि असंतुष्टों के अभियान के गति पकड़ने पर आलाकमान क्या रवैया अख्तियार करता है ?

—सुधीर सक्सेना

सांसद के कारखाने में दुर्घटना

प्रदूषण की अनदेखी : यूनीअल्केम कारखाना और सांसद प्रतापभानु शर्मा (इनसेट)

भोपाल से लगभग २५ किमी दूर रायसेन जिले के दीवानगंज में स्थित है, यूनीअल्केम फर्टिलाइजर्स लि० नामक कारखाना। इस कारखाने में भागीदार हैं, विदिशा से निर्वाचित इंका सांसद प्रतापभानु शर्मा। १९८४ में स्थापित इस कारखाने में गंधक-अम्ल और सुपर फास्फेट का उत्पादन होता है। प्रतापभानु शर्मा की हैसियत इस कारखाने में उपाध्यक्ष की है, जबकि संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं धरमसी मोरारजी केमिकल्स के आरएम गोकुलदास। जयंत गौर इस कारखाने के प्रबंध संचालक हैं। आईडीबीएल और एबीएन के ऋण से लगभग पांच करोड़ रुपयों की लागत से स्थापित इस कारखाने में रातदिन यानी तीन पालियों में काम होता है।

२५ मार्च, '८८ को 'सी' शिफ्ट यानी रात १२ बजे से प्रातः ८ बजे की पाली में २१ वर्षीय भोगीराम नामक मजदूर काम कर रहा था कि तड़के करीब ४ बजे तेजाब की पाइप लाइन फट गयी और भोगीराम तेजाब से बुरी तरह झुलस गया। भोगीराम को उपचार के लिए विदिशा चिकित्सालय में भरती किया गया, जहां से उसे दस दिन बाद छुट्टी दे दी गयी।

हादसे की शुरुआत : यूनीअल्केम में दुर्घटना का यह पहला प्रसंग नहीं है। कारखाने में इसके पूर्व भी हादसा हो चुका है। करीब चार माह पूर्व यही कारखाना इलाके में प्रदूषण का बायस बन चुका है। १० दिसंबर को इस कारखाने से सल्फर डाई आक्साइड गैस रिसी थी, जिसका सीधा प्रभाव फसल पर पड़ा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिसन की पूर्व संध्या को गंधक-अम्ल बनाने के लिए भट्ठी में करीब पांच सौ किलोग्राम गंधक झोंका गया था। अम्ल बनाने की प्रक्रिया में गंधक को पहले सल्फर डाई आक्साइड और फिर ट्राई आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उस रात बिजली चली जाने से केवल पहला चरण ही पूरा हो सका और सल्फर डाई आक्साइड रिस कर हवा में घुल गयी। चूंकि, उस रात आकाश में घना कोहरा था, अतः गैस विसर्जित होने के बजाय खेतों में फैल गयी, जिसके कारण करीब तीन सौ एकड़ में गेहूं व चने की फसल पीली पड़ गयी। गैस रिसन की खबर प्रबंधकों के साथ-साथ सांसद शर्मा को लगनी स्वाभाविक थी। वह तीन दिन बाद दीवानगंज आये और कारखाने से एक फर्लांग दूर स्थित दीवानगंज गांव, जो उन्हीं के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है, में किसानों की सभा की। ग्रामीणों व किसानों को गैस के शारीरिक दुष्प्रभाव व फसलों पर नुकसान का अंदाजा इसलिए नहीं हो सका था, क्योंकि गैस रिसन व सांसद के आगमन के दरम्यान दो दिन बारिश होती रही थी। सांसद शर्मा ने ५ अप्रैल की रात्रि को दूरभाष पर 'माया' से चर्चा में स्वीकार किया कि दिसंबर में कारखाने से गैस रिसी थी। उन्होंने कहा, "गैस रिसने से किसी व्यक्ति या फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, बल्कि गैस ने बारिश की वजह से पानी में घुल कर फसल के लिए लाभकारी खाद का काम किया था। इस घटना के कारण किसानों को खेतों में औसत उत्पादन से दुगुनी तक फसल प्राप्त हुई।"

पृष्ठभूमि : प्रतापभानु शर्मा ने विदिशा के सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। वह विदिशा स्थित यूनियन पेस्टीसाइड्स कारखाने के स्वामित्व में भी नर्मदा प्रसाद शर्मा और जयंत गौर के साथ भागीदार हैं। जयंत गौर यूनीअल्केम में प्रबंध निदेशक हैं। यूनियन पेस्टीसाइड्स में उत्पादित कीटनाशकों का सेना व सरकारी विभागों को आपूर्ति के साथ-साथ विदेशों को भी निर्यात होता है। अभिप्राय यह है कि कंपनी खासे मुनाफे में चल रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार यूनीअल्केम की स्थापना के लिए विदिशा के पचास लोगों से पचास-पचास हजार रुपयों के शेयर के एकत्र करने की जुगत भिड़ायी गयी और २५ लाख रुपए इस प्रकार आनन-फानन में इकट्ठे हो गये।

प्रतापभानु इंका टिकट पर लोकसभा के लिए

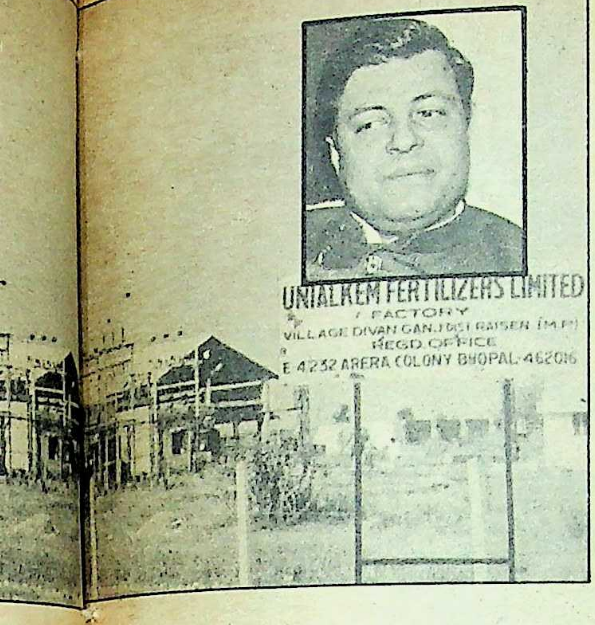
UNIALKEM FERTILIZERS LIMITED
FACTORY
VILLAGE DIVAN GANJ DIST RAISEN (M.P.)
REGD OFFICE
E 4/232 ARERA COLONY BHOPAL-462016

सर्वप्रथम १९८० में निर्वाचित हुए और फिर १९८४ में पुन: विजयी रहे। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय प्रकाशचंद सेठी को है, जिनके वह बरसों तक प्रियपात्र रहे। प्रिय रंजन दासमुंशी ने उन्हें मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, किंतु अंबिका सोनी के काल में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। सेठी के चहेते मोतीलाल वोरा के मुख्यमंत्री बनने पर प्रतापभानु वोरा के 'किचन कैबिनेट' के सदस्य कहलाने लगे। इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि वोरा जब मुख्यमंत्री थे, तो वह उनके सबसे नजदीकी सांसद थे। वोरा और दिग्विजय में ठनी, तो वह प्रदेश इंकाध्यक्ष पद के लिए वोरा की पहली पसंद थे, लेकिन इस नेपथ्य-अभियान में वोरा की गोटियां सही नहीं बैठीं और प्रतापभानु संगठन के मुखिया का पद पाने से वंचित रहे।

परवर्ती कथा : सांसद के इस आशय के कथन की पुष्टि कारखाने के समीपवर्ती गांवों के लोग भी करते हैं कि कारखाने से रिसी गैस से उन्हें लाभ हुआ। जो बात सांसद शर्मा ने 'माया' से दूरभाषिक बातचीत में कही, वही बात उन्होंने तब किसानों के बीच भी कही थी। दीवानगंज गांव के सरपंच गौहर मियां कहते हैं कि गैस से कोई नुकसान नहीं हुआ। फसल में थोड़ा पीलापन जरूर आ गया था। भाई गुलाम अली को फैक्ट्री से मिली क्षतिपूर्ति की बारह सौ रुपयों की रकम को वह अतिरिक्त मुनाफा मानते हैं। कृषक सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रथमपाल सिंह की दृष्टि में गैस रिसना वरदान था। फसल को मुफ्त में खाद मिल गयी और मुआवजे के २७०० रुपए मिले सो अलग। आसपास के गांवों का हरेक व्यक्ति सांसद महोदय और कारखाने का गुन गाता रहा हो ऐसा भी नहीं है। १६ दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टरों में भरकर रायसेन पहुंचकर जिलाध्यक्ष कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया। कंपनी के एमडी जयंत गौर के अनुसार कंपनी ने तीस हजार रुपए की रकम मुआवजे के तौर पर किसानों में बांटी। इसे असत्य मानने का कोई आधार नहीं है, किंतु इस मामले में दो सवाल उठते हैं। पहला यह कि शासन ने रिसन व प्रदूषण पर क्या कार्रवाई की और दूसरा यह कि अगर बारिश न होती, तो लोगों व फसल पर क्या प्रभाव पड़ता?

सूचनाएं बताती हैं कि सांसद की मान-मर्यादा का खयाल रखते हुए शासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रिसी गैस से लाभ हुआ या हानि, यह दीगर मुद्दा है, मगर गैस का रिसना दुर्घटना है या नहीं? पहली मई' ८७ को दीवानगंज में ही स्थित सोबती केमिकल्स से ओलियम गैस रिसी थी, तो शासन तत्काल सक्रिय हो गया था। प्रदूषण निवारण मंडल के डा० सिंह की रपट पर पुलिस ने २४ घंटों के भीतर कारखाने के मालिक को बगैर इसका लिहाज किये धर पकड़ा था कि वह दिल का मरीज है। किसानों ने कलेक्टर-कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, लेकिन कलेक्टर पांडे ने प्रदूषण अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर कार्यालय से प्रदूषण निवारण मंडल को केवल डीओ लेटर ही भेजा गया। पुलिस ने केस के बजाय डायरी में महज सूचना दर्ज कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली। प्रदूषण निवारण मंडल, जिस पर सर्वाधिक दायित्व था, ने कारखाने को महज खानापूरी के लिए नोटिस देकर हाथ-पर-हाथ धर लिया। मंडल ने यह देखना गवारा नहीं किया कि कारखाने में एयर मानीटरिंग उपकरण लगे हैं या नहीं, उत्सर्जित जल में तेजाब की अधिक मात्रा की रोकथाम की व्यवस्था की गयी है या नहीं और भविष्य में बिजली जाने पर फिर दुर्घटना न हो, इस हेतु तीनों चरणों के लिए डीजल गन के उपयोग का मुकम्मल इंतजाम हुआ है या नहीं? इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि सल्फर डाई आक्साइड सांस के साथ शरीर में जाकर विकार उत्पन्न करती है।

ताजा हादसा : अब दूसरे और ताजे प्रसंग पर आयें। दूरभाष पर चर्चा में श्री शर्मा ने कहा, "आप जिसकी बात कर रहे हैं, वह हमारे यहां काम ही नहीं करता था। हमारे यहां तेजाब से किसी के झुलसने की कोई घटना ही नहीं घटी। आपको किसी ने गलत खबर दी है।" सांसद ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि संवाददाता का दुविधा में पड़ना स्वाभाविक था। तय हुआ कि कारखाने जाकर श्रमिकों व प्रबंधकों से बात की जाये। गैस रिसन के बाद प्रबंधकों से एक बार चर्चा हो चुकी थी, लेकिन इस दफा उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। मजदूरों से बातचीत से लगा कि शर्मा का बयान यथार्थ से परे है। या तो उन्हें सही बात की जानकारी नहीं दी गयी है या फिर वह गलतबयानी कर रहे हैं। सचाई की तलाश में जरूरी था कि भोगीराम को तलाशा जाये। अंततः वह अपने गांव में मिला। उसने शरीर उघाड़कर गर्दन व पीठ पर तेजाब के छींटों का असर दिखाया। उसकी एक आंख में भी तेजाब का छींटा पड़ा है, जिस दुष्प्रभाव आंख की रोशनी पर भी पड़ा है। भोगीराम ने बताया कि उस शिफ्ट 'बी' में ही तेजाब पाइप का ज्वाइंट लीकेज कर चुका था, किंतु प्रबंधकों ने गौर नहीं किया। लीकेज के कारण बाबूलाल नामक श्रमिक पर कुछ छींटे भी पड़े थे। भोगीराम के अनुसार उस रात पवन कुमार चतुर्वेदी उसकी शिफ्ट के इंचार्ज थे। हेल्पर ओम प्रकाश और बलराम तथा आपरेटर हरी सिंह दुर्घटना के गवाह हैं और वे ही उसे अस्पताल ले गये थे।

श्रमिक के बयान से यकीनन शंका उत्पन्न होती है। यदि भोगीराम यूनीअल्केम में काम नहीं करता, तो वह ये नाम कैसे बता रहा है? वह एकबारगी झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत यूनीअल्केम का अटेंडेंस कार्ड तो झूठ नहीं बोलता। भोगीराम द्वारा दिखाया गया कार्ड सांसद के कथन की बखिया उधेड़ देता है और रही सही कसर पूरी कर देता है, उसका यह रहस्योद्घाटन, "गौर साहब ने तीन सौ रुपये भेजे थे, जो हमने नहीं लिये। मुझसे यह भी कहा गया था कि कह देना कि घर पर बैटरी चार्ज करने के लिए बोतल में एसिड भर कर ले गया था। बोतल ऊपर रख रहा था कि वह गिर गयी और मैं जख्मी हो गया।" यह गौर साहब और कोई नहीं कारखाने के प्रबंध संचालक जयंत गौर हैं, जो एक कारखाने में प्रतापभानु शर्मा के भागीदार भी हैं।

—सुधीर सक्सेना, एसपी त्रिपाठी के साथ

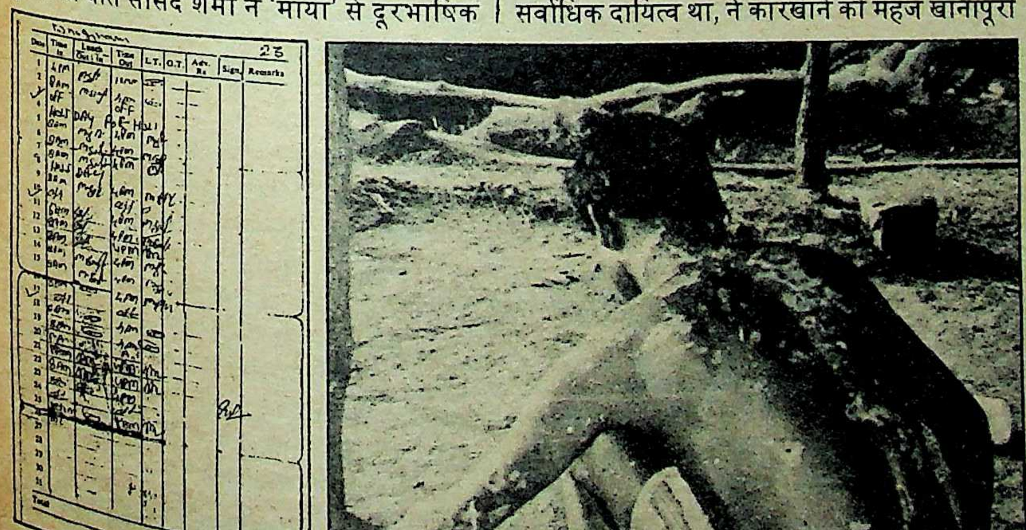

हादसे के दिन काम पर: भोगीराम (दायें) का अटेंडेंस कार्ड

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत
ASPRO
draws out pain faster
सरदर्द का
बेहतरीन
उपचार
दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा
daCunha/ASI/4187 Hin

साक्षात्कार/ एमएस सिंहदेव, (मुख्यसचिव)

राजनीति में आने का इरादा नहीं

"वर्तमान प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों की देन है। उसमें वर्तमान परिस्थितियों और जनाकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन की काफी गुंजाइश है—" मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेट्री) और सरगुजा रियासत के भूतपूर्व महाराज मदनेश्वर शरण सिंहदेव मानते हैं कि प्रशासन तंत्र की सार्थकता और सफलता इसमें है कि उसके कार्यों से उस व्यक्ति को संतुष्टि हो, जिसके लिए वह निर्मित व सचेष्ट है। उनकी यह भी मान्यता है कि शासकीय सेवक को शासन की प्रत्येक नीति और निर्णय को तत्परता व ईमानदारी से लागू करना चाहिए, भले ही वह उससे असहमत क्यों न हो। अंबिकापुर में २ जून, १९३० को राजपरिवार में जन्मे सिंहदेव की शिक्षा-दीक्षा राजकुमार कालेज, रायपुर, यूइंग क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इतिहास में पीएचडी के दरम्यान ही वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिये गये और १९५४ में आईएएस संवर्ग में प्रविष्ट हुए। ९ मार्च को सिंहदेव केसीएस आचार्य के स्थान पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव बने। प्रस्तुत है, क्रिकेट और आखेट के शौकीन सिंहदेव से सामयिक संदर्भों में 'माया' की बातचीत:

माया: प्रदेश गत वर्ष सूखे और पेयजल के अभूतपूर्व संकट की गिरफ्त में था। क्या आपकी दृष्टि में शासन इनसे निपटने में पूर्णतः सफल रहा?

सिहदेव: यह सही है कि वर्ष १९८५-८६ एवं ८७ में अपर्याप्त एवं असामयिक वर्षा होने के कारण प्रदेश के कई भागों में सूखे की स्थिति रही है। लेकिन वर्ष १९६६-६७ एवं वर्ष १९७९-८० के मुकाबले अकाल का प्रभाव बहुत ही कम रहा है। सामान्यतः अकाल में हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि प्रभावित जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, पीने के पानी की कोई कमी न हो, जरूरतमंद लोगों को मजदूरी मिलती रहे। यदि इस दृष्टि से हम शासन द्वारा उठाये गये कदमों का आकलन करें, तो पाते हैं कि गत तीनों वर्षों में हम प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक राहत पहुंचाने में सफल हुए हैं।

माया: अपने सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव के आधार पर आप नौकरशाही और नेताओं के बीच किस प्रकार के संबंधों के हिमायती हैं?

सिहदेव: मेरी समझ में नेताओं और अधिकारियों के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। राजनीतिक नेताओं को नीति निर्धारित करने के अलावा जन-समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए और अधिकारियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे यथाशक्ति निर्धारित नीति का पालन करने का पूरा प्रयास करें एवं जो जन-समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत की जायें, उनका हल निकालने का पूरा प्रयास करें। यदि दोनों अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करें , तो कभी भी दोनों के बीच कोई टकराहट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा और जो मधुर संबंध बनेंगे उससे जन मानस को लाभ भी होगा।

माया: यह कहां तक सही है कि पिछले कुछ सालों में प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और इस तरह के हस्तक्षेप से प्रशासन तंत्र की गति और गुणवत्ता में गिरावट आती है?

सिहदेव: यह स्पष्ट है कि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार है कि जनसाधारण की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचायें और यह अपेक्षा करें कि उन समस्याओं का यथासंभव हल हो। देश में जैसे-जैसे जागृति आ रही है, वैसे-वैसे जनसाधारण में कार्य करने वाले कार्यकर्ता जन-समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में अधिक सक्रिय हो गये हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी प्रकरण हों, जिनमें राजनीतिक दबाव प्रशासन पर आता हो और कुछ हस्तक्षेप भी होता हो, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासन में कोई गिरावट आयी है। आज प्रशासनिक ढांचा वही है जो अंग्रेजों के समय था। उन्हें भी अपने आपको इस तरह बनाना होगा कि वे जन-समस्याओं एवं जनाकांक्षाओं के प्रति सजग हों। किंचित राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रकरणों को लेकर एक सामान्य निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा। हमें तो चाहिए कि हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों एवं प्रशासन में बैठे लोगों के मध्य एक ऐसा समन्वय स्थापित करें, जिससे कि जनहित के कार्यों को तत्परता से निपटाया जा सके और जन-मानस यह महसूस करे कि उसके लिए ही शासन कार्य कर रहा है।

माया: प्रायः यह देखा गया है कि नौकरशाह अहंमन्यता में डूबे रहते हैं और लोगों, खासतौर पर आम लोगों से ठीक से पेश नहीं आते। ऐसे में क्या यह सच नहीं है कि समस्याओं के निराकरण और प्रशासन के साथ जन-सहयोग—दोनों में दिक्कत होती है?

सिहदेव: यह भी एक सामान्य प्रकार की धारणा है कि प्रशासनिक अधिकारी अहंमन्यता में डूबे रहते हैं, जिसके कारण समस्याओं का निराकरण सही प्रकार से नहीं हो पाता। हो सकता है कि इस मनोवृत्ति के कुछ लोग हों, लेकिन अधिकांश लोग तो यह प्रयास करते हैं कि वे जन-समस्याओं को समझें और उनका यथाशीघ्र निराकरण करें।

माया: प्रशासन तंत्र में सर्वोच्च पद पर होने के नाते क्या आपने तंत्र को अधिक कारगर बनाने के लिए कोई कदम उठाया है?

सिहदेव: मेरे पास समय ही बहुत कम है कि मैं प्रशासन में समुचित परिवर्तन करने का प्रयास करूं। लेकिन फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि प्रशासन जन-समस्याओं के प्रति सजग हो और उनका शीघ्र निराकरण करने का पूरा प्रयास हो।

माया: नौकरशाही पर बरसों से लालफीताशाही का आरोप लग रहा है। देखा यह गया है कि अगर व्यक्तिगत रुचि या ऊपर से दबाव न हो, तो फाइलें कई-कई दिनों तक तो क्या, महीनों आगे नहीं सरकती हैं। क्या यह व्यापक असंतोष पनपने का कारण नहीं है?

सिहदेव: यह सही है कि प्रशासन पर लालफीताशाही का आरोप लगाया गया है। कुछ हद तक यह आरोप सही भी है। प्रशासन को जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम निश्चित समय सीमा में प्रकरणों का निपटारा करें और इस दिशा में कारगर कार्यवाही होना अत्यंत आवश्यक है।

माया: मध्य प्रदेश में राजनीतिक लाबियों की चर्चा पत्र-पत्रिकाओं में अकसर होती रहती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश में आईएएस भी लाबियों में बंटे हुए हैं?

सिहदेव: मैं आईएएस एसोसिएशन्न का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और ३४ वर्षों से इस सेवा का अधिकारी रहा हूं। यह संभव है कि मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों में ऐसा समन्वय न हो, जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अधिकारियों में विभिन्न लाबियां होने का जो आरोप है, वह सही नहीं है।

माया: एक पूर्व रियासत और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण आपके बारे में यह कथन कहां तक सही है कि आप शासकीय सेवा के बाद सक्रिय राजनीति में जायेंगे?

सिहदेव: कई लोगों का यह खयाल है कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में आऊंगा लेकिन अभी भी मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी, मेरा बड़ा लड़का तथा मेरे कई अन्य रिश्तेदार सक्रिय राजनीति में हैं और इसलिए मेरा वर्तमान में राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।

—सुधीर सक्सेना

विधायक कत्याल की हत्या

आतंकवादियों के नापाक इरादे

४ अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने बड़े जोरदार शब्दों में घोषणा की थी कि आतंकवादी इस प्रदेश में घुस नहीं सकते, लेकिन इस घोषणा के १८ घंटे बाद ही ५ अप्रैल को सुबह साढ़े आठ बजे कानपुर में सरेआम कांग्रेसी विधायक विलायती राम कत्याल को अंगरक्षक सहित आतंकवादियों ने बड़े इतमीनान से गोलियों से छलनी कर दिया। पहले तो गृहमंत्री इसे आतंकवादी हत्या मानने से ही इनकार करते रहे, लेकिन जब आतंकवादी हत्यारे पकड़े गये और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, तो राज्य सरकार कहने लगी कि हमने तो कत्याल को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये थे तथा राज्य सरकार इससे अधिक और कर ही क्या सकती थी, हत्या तो श्रीमती गांधी और जनरल वैद्य की भी हो चुकी है। सवाल उठता है कि सरकार को एक लंबे अरसे से समाचार पत्रों व विधायकों द्वारा प्रदेश में आतंकवादी अड्डों व गतिविधियों की सूचना मिलती रही थी और खुद कत्याल को भी १३ अप्रैल से पूर्व मार देने का धमकी भरा पत्र मिला था, फिर सरकार इस ओर से आंखें क्यों मूंदे रही और वह प्रदेश की जनता को क्यों गुमराह करती रही? कत्याल की हत्या के पीछे आतंकवादियों का इरादा क्या था? क्या यह हत्या आतंकवादियों की राज्यव्यापी साजिश की एक कड़ी है? :

शासन अंधेरे में : कांग्रेस-इ विधायक विलायतीराम कत्याल (इनसेट) का शोकसतप्त परिवार और प्रशंसक

इसी ५ अप्रैल की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे कांग्रेस-इ विधायक विलायती राम कत्याल की हत्या उस समय की गयी, जब वह रतनलाल नगर (धबौली) स्थित आवास से अपने मित्र देशराज मलिक के यहां गोविंदनगर जा रहे थे। वह स्कूटर चला रहे थे। उनका अंगरक्षक संतोष यादव पिछली सीट पर बैठा था। उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस-इ विधि प्रकोष्ठ के संयुक्तसचिव संतोष शुक्ल भी एक अलग स्कूटर से चल रहे थे। दोनों स्कूटर अभी प्रकाश मार्केट चौराहे के निकट पहुंचे ही थे कि सड़क के किनारे बायीं ओर पेड़ की छांव में खड़ी एक सफेद मारुति कार से टेक लगाये दो युवकों ने स्वचालित रायफलों से धुआंधार गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पहले गोलियां कत्याल के अंगरक्षक को निशाना बनाकर चलायी गयी थीं।

हमलावरों का निशाना अचूक था। अंगरक्षक संतोष यादव गोली लगते ही स्कूटर से नीचे गिर पड़ा। कत्याल ने मौके की नाजुकता समझ स्कूटर से भाग जाना चाहा, लेकिन ५-७ मीटर आगे जाकर ही, वह स्कूटर सहित गिर पड़े। साथ के स्कूटर चालक संतोष शुक्ल के बायें हाथ में भी कई गोलियां लगीं और वह स्कूटर से लुढ़ककर सड़क के दूसरी ओर जा गिरे। दोनों हमलावर अभी भी लगातार गोलियां चला रहे थे। वे तेज कदमों से जमीन पर पड़े कत्याल और उनके अंगरक्षक के पास पहुचे। कत्याल के शरीर को उन्होंने हिलाडुलाकर देखा। फिर उनके शरीर पर पास से कई गोलियां दाग, यह यकीन कर लिया कि वह मर चुके हैं। यह सब कुछ उस भीड़भाड़ पूर्ण सड़क पर आनन-फानन हो गया। जब तक लोग माजरा समझते, वे दोनों मारुति कार पर सवार होकर भाग निकले। उ सफेद रंग की कार पर कोई नम्बर प्लेट नहीं लग थी। जिस समय हमलावर गोलियां चला रहे थ कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा उनका तीसरा साथी इंजन स्टार्ट किये हुए था।

कोई तीन मिनट के अन्दर ही हमलावर अपना 'काम' पूरा कर भाग निकले थे। उन्होंने जिस तरह से गोलियां चलायी थीं और जिस प्रकार स्वचालित अस्त्र उनके पास थे, उससे ऐसा लग रहा था, जैसे वे इस तरह के काम के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित थे। निःसंदेह विधायक कत्याल की हत्या

नियोजित तरीके से की गयी थी, क्योंकि हमलावरों को यह बखूबी मालूम था कि कत्याल अपने स्कूटर द्वारा उस रास्ते से गुजरेंगे। कत्याल और उनके अंगरक्षक की हत्या के कोई बीस मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंचनेवाले पुलिस अधीक्षक (नगर) डीबी राय पहले पुलिस अफसर थे। तब तक मौके पर घायल पड़े संतोष शुक्ल को पास के एक नर्सिंग-होम में पहुंचाया जा चुका था। नर्सिंग-होम से ही किसी ने इस घटना की सूचना फोन पर पुलिस को दी थी। मौके पर कारतूस के ३४ खोखे पाये गये थे जो स्वचालित रायफल (एस एस आर) के थे। घटना के चश्मदीद गवाह तथा घायल संतोष शुक्ल से पुलिस को जो जानकारी मिली, उसके अनुसार हत्यारों की उम्र २७-२८ के आसपास थी। वारदात के समय दोनों हमलावर नीली जीन्स, चेकदार कमीज पहने थे तथा माथे पर नीला पटका बांधे थे। उनकी दाढ़ियां घनी, किन्तु खुली हुई थीं। उनके पास सफेद रंग की मारुति कार थी, जिस पर नम्बर प्लेट नहीं थी।

पुलिस जांच: इस घटना के आधे घंटे के अन्दर ही पुलिस ने कानपुर से बाहर जानेवाले सभी रास्तों की नाकेबंदी कर ली। वारदात की खबर राज्य मुख्यालय पर गृहसचिव और पुलिस महानिदेशक को भी दे दे गयी। उस दिन विधानसभा की प्रस्तावित बैठक सूचना मिलते ही शोक में स्थगित कर दी गयी। प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित आनन-फानन कानपुर पहुंच गये।

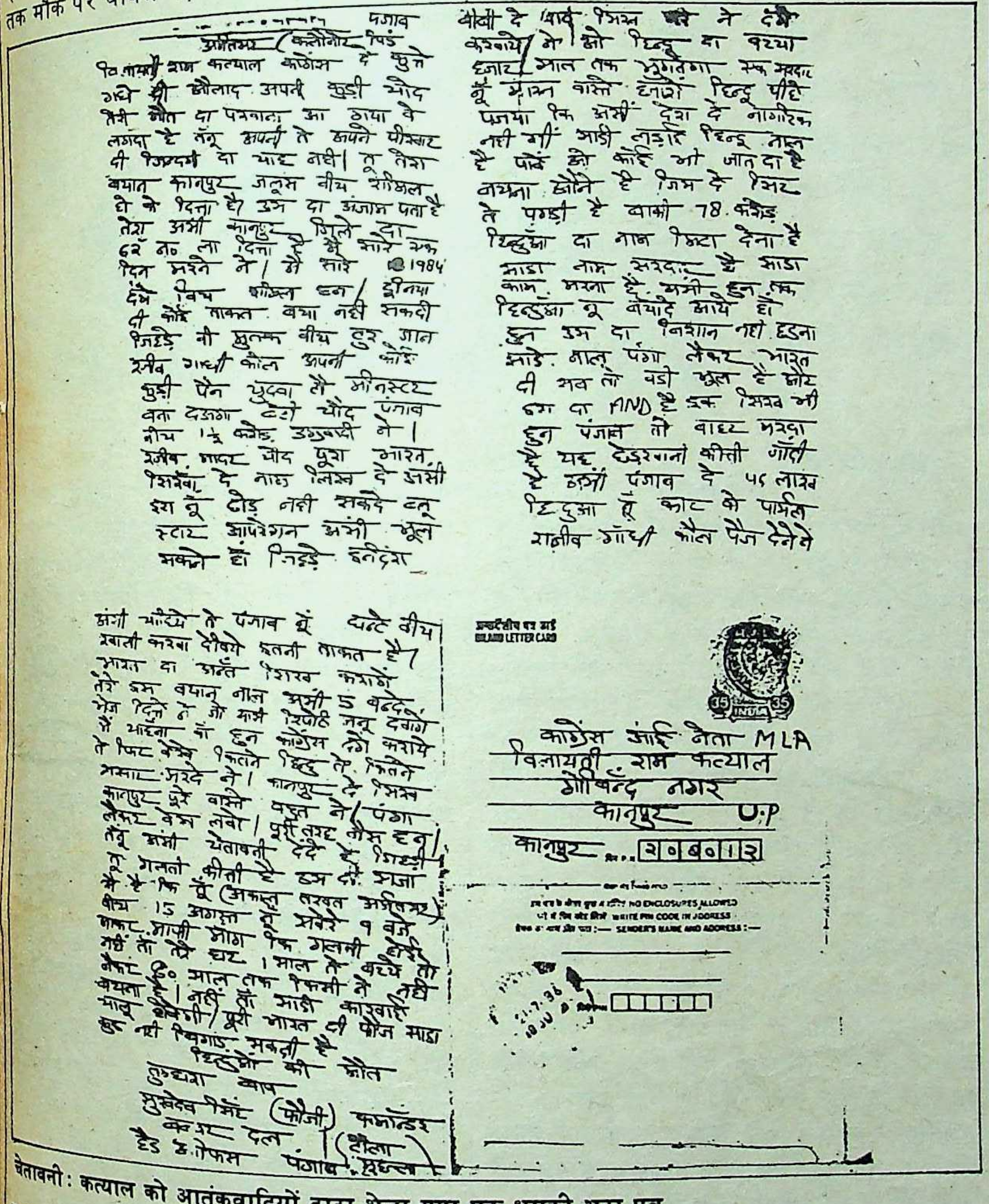

पंजाब
अंतिम (कलोनौर पिंड

वि.नायती राम कत्याल कांग्रेस दे कुत्ते
गधे दी औलाद अपनी कुड़ी औद
तेरी मौत दा परवाना आ गया वे
लगदा है तैनू अपनी ते अपने परिवार
दी जिन्दगी दा भार नहीं। तू तेरा
बयान कानपुर जलूस वीच रौला
दे के दित्ता है उस दा अंजाम पता है
तेरा असीं कानपुर जिले दा
62 नं० ला दित्ता है मैं मारे इक
दिन मरने ने। जो सारे 1984
दंगे विच शामिल हन। दुनिया
दी कोई ताकत बचा नहीं सकदी
जिहड़े नी छुत्क वीच हुए। राजीव
गांधी कौल अपनी कोई
कुड़ी पैन खुदवा तो मीनस्टर
बना दउगा [illegible] औद पंजाब
वीच 1½ करोड़ उग्रवादी ने।
रजीव बाप औद पूरा भारत
सिखां दे नाल लिख दे असीं
इस नू छोड़ नहीं सकदे तू
स्टार आपरेशन असीं भूल
सकदे हां जिहड़े हरिंदर

बीबी दे बाद सिख दे ने दंगे
करवाये ने जो हिन्दू दा बच्चा
हजार साल तक भुगतेगा इक मरदा
नू मारन वास्ते हजारों हिन्दू पीहे
पजया कि असीं देश दे नागरिक
नहीं हां। साडी लड़ाई हिन्दू नाल
है पावें जो कोई भी जात दा है
बचना जोने है जिस दे सिर
ते पगड़ी है बाकी 78 करोड़
हिन्दुआं दा नाम मिटा देना है
साडा नाम सरदार है साडा
काम मरना है। असीं हुन इक
हिन्दुआं नू बेयादे आये हां
हुन उस दा निशान नहीं रहना
साडे नाल पंगा लैकर भारत
दी अब तो बड़ी भूल है जोर
इस दा AND है इक सिख भी
हुन पंजाब तो बाहर मरदा
है यह टेडरगानो कीती गोली
है असीं पंजाब दे 48 लाख
हिन्दुआं हूं काट के पार्सल
राजीव गांधी कौल पैज देने ने

असीं आंख्ये ते पंजाब हूं घट्टे वीच
रखाली करवा दीत्ते इतनी ताकत है।
भारत दा अंत सिख करांगें
तेरे इस बयान नाल असीं 5 बन्दे
भेज दित्ते ने जो सभी सिपाही जनू देवांगे
मैं आहना वां हुन कांग्रेस नौं कराये
ते फिट कैसे कितने हिन्दु ते कितने
मुसलमान मरदे ने। कानपुर दे सिख
कानपुर छोड़े वास्ते पक्त ने। पंगा
लैकर देख लवो। पूरी तरह तैयार हन।
तैनूं असीं चेतावनी दंदे हैं जिन्हीं
तू गलती कीती है इस दी सजा
मैं है कि तूं (अकाल तख्त अमृतसर)
वीच 15 अगस्त दे सवेरे 9 वजे
जाकर माफी मांग कि गलती होई
नहीं तां तेरे घर। मात ते बच्चे तो
लेकर 80 साल तक किसी ने नहीं
बचना है। नहीं तां साडी कारवाई
मात्र [illegible]। पूरी भारत दी फौज साडा
कुछ नहीं बिगाड़ सकदी है
हिन्दुओं की मौत
तुम्हारा बाप
सुखदेव सिंह (फौजी) कमांडर
केजर दल (टौला
हैड ऑफिस पंजाब। [illegible]

अन्तर्देशीय पत्र कार्ड
INLAND LETTER CARD

कांग्रेस आई नेता MLA
विलायती राम कत्याल
गोविन्द नगर
कानपुर U.P
कानपुर 208012

इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए NO ENCLOSURES ALLOWED
पते में पिन कोड अवश्य लिखिए WRITE PIN CODE IN ADDRESS
भेजने वाले का नाम और पता :— SENDER'S NAME AND ADDRESS :—

चेतावनी: कत्याल को आतंकवादियों द्वारा भेजा गया एक धमकी भरा पत्र

गृहमंत्री जब पुलिस अधिकारियों के साथ शव-विच्छेदन गृह पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद भीड़ ने 'मुर्दाबाद और वापस जाओ' के नारे लगाये। कुछ लोगों ने, जिनमें अधिकांश जनमोर्चा के कार्यकर्ता थे, गृहमंत्री को जबरन चूड़ियां पहनाने की कोशिश की।

शाम तक लखनऊ से आतंकवाद विरोधी दस्ता, गुप्तचर विभाग की टीम तथा कई बड़े पुलिस अधिकारी कानपुर पहुंच गये। मौके पर पाये गये कारतूसों के खोखों की जांच से यह पता चला कि हत्यारों ने ९ एमएम चाइनीज मार्क एके-४७ स्वचालित रायफल का इस्तेमाल किया था। अगले दिन कत्याल की शवयात्रा में काफी भीड़ थी। उस दिन पूरा कानपुर शोक में बंद रहा। शव यात्रा में सिखों की भी तादाद काफी थी।

अंधेरे में तीर: पुलिस की सारी चौकसी और वाहनों की व्यापक तलाशी के बावजूद, पुलिस को अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सुराग न मिलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आतंकवादी कार्यवाही मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, जबकि सारे हालात इसे आतंकवादी कार्यवाही बता रहे थे। कानपुर में गोविंदपुर ही वह जगह थी, जहां १९८४ में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के प्रतिक्रियास्वरूप भड़के दंगों में कुछ सिखों की हत्याएं हुई थीं। ५३ वर्षीय विलायती राम कत्याल इसी क्षेत्र के विधायक थे। वह आतंकवाद के कट्टरविरोधी के रूप में विख्यात थे। विधानसभा के सदस्यों के जीवन परिचय वाली पुस्तक (१९८५) में कत्याल का जीवन परिचय देते हुए इस बात का खास उल्लेख किया गया था। इतना ही नहीं कत्याल को आतंकवादियों द्वारा १६ फरवरी, १९८६ से मार्च, १९८८ तक धमकी भरे छह पत्र भी मिले थे। अंतिम पत्र में उन्हें १३ अप्रैल से पूर्व मार डालने की धमकी दी गयी थी। राज्य सरकार उन्हें अंगरक्षक देकर और उनके घर पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर निश्चित हो गयी थी। विडंबना यह है कि इस हत्याकांड के १८ घंटे पहले तक उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित बड़े जोरदार शब्दों में कहते रहे थे कि राज्य में आतंकवादियों की कहीं भी कोई गतिविधि नहीं है। ४ अप्रैल को लोकदल-ब विधायक रामशरण दास ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखते हुए, जब यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के १० जिलों में आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना लिये हैं तो गृहमंत्री ने फरमाया, "आतंकवादी इस प्रदेश में घुस नहीं सकते। हमारी पुलिस आतंकवादियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है, हम उन्हें उत्तर प्रदेश में घुसने ही नहीं देंगे।" ऐसा नहीं है कि विधायक रामशरण दास पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रदेश में आतंकवादी अड्डों के होने की जानकारी दी थी, बल्कि पिछले नौ महीनों में कानपुर में तैनात कम-से-कम पांच पुलिस सबइंस्पेक्टरों ने अपने अफसरों को रिपोर्ट दी थी कि कानपुर और आसपास के जिलों में आतंकवादी वारदात कर सकते हैं। ये रिपोर्टें भी पुलिस फाइल में देखी जा सकती हैं, लेकिन इन इंस्पेक्टरों की रिपोर्टों को अनदेखा कर दिया गया। वस्तुतः १९८६ से ही पत्र-पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के गिरोहबंद होने की खबरें देती रही थीं। इन खबरों में कहा गया था कि कानपुर में आतंकवादियों ने आत्मघाती दस्ते बना लिये हैं। डेढ़ वर्ष पूर्व कानपुर से रवाना हुई राज्य परिवहन की दो बसों में आतंकवादियों ने ट्रांजिस्टर-बम रखे थे, जिनमें से एक बरामद हो गया था, लेकिन दूसरे ट्रांजिस्टर-बम ने उन्नाव में दो लोगों के प्राण ले लिये थे। लेकिन लानत की बात यह है कि प्रदेश का प्रशासन और पुलिस इन सब संकेतों को अनदेखा करता रहा। इसी वर्ष ४ जनवरी को रंजीत नगर स्थित ओरियंटल कामर्स बैंक में जब डाका पड़ा, तब

भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे आतंकवादी कार्यवाही नहीं माना और इस डकैती को राजू भटनागर गिरोह के सिर मढ़ दिया था। आतंकवादी खतरे को राज्य सरकार ने इस कदर अनदेखा किया था कि कत्याल की हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे गृहमंत्री दीक्षित ने कहा, "फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि यह करामात आतंकवादियों की है। घटना की जांच आतंकवाद विरोधी सेल से करायी जायेगी और जांच के नतीजों के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।"

लेकिन पुलिस की जांच-पड़ताल और खोजबीन नकारा साबित हो रही थी। ५ और ६ अप्रैल भी गुजर गयी। कानपुर शहर की चौतरफा नाकेबंदी किसी काम नहीं आयी।

राष्ट्रप्रेमी सिख : यदि एक राष्ट्रप्रेमी सिख ने सुराग न दिया होता, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बस की बात नहीं थी कि वह अपराधियों तक पहुंच जाती। वह इस घटना को भी निजी दुश्मनी का रूप देकर या तो अंधेरे में भटकती रहती या इस मामले को दाखिल दफ्तर करके फाइल बंद कर देती। लेकिन संयोग से साकेत नगर इलाके में गुरुदर्शन सिंह भाटिया के 'भाटिया लाज' के बाहर खड़ी एक मारुति कार पर लगी सर्वथा नयी नेमप्लेट को देखकर एक सिख को संदेह हो गया। कत्याल की हत्या के बाद हमलावरों के कपड़ों का जो विवरण अखबारों में छपा था, वैसे ही कपड़े पहने दो लोगों को उसने देखा, तो वह उन्हें पहचान गया। ये पीके शर्मा और राजविंदर थे, जो भाटिया लाज में छात्र के रूप में पिछले ९ महीनों से टिके थे। वह सिख इन दोनों लोगों को जानता था और वह यह भी जान गया था कि ये लोग इस कार से नैनीताल जा रहे हैं।

बस, फिर क्या था। इस राष्ट्रप्रेमी सिख ने तत्काल पुलिस महानिरीक्षक बलवीर सिंह बेदी (जो स्वयं सिख हैं) को उक्त युवकों की संदेहजनक गतिविधियों की जानकारी दी और यह भी बताया कि ये लोग नैनीताल के लिए रवाना हुए हैं और कार का नंबर डीडीडी—९८८० है। यह खबर मिलते ही बेदी ने उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली और नैनीताल की पुलिस को वायरलेस कर उक्त नंबर की कार को ढूंढ़ने का आदेश दे दिया। ७ अप्रैल की शाम को कानपुर पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर बरेली पुलिस ने शहर में छानबीन शुरू की, तो उन्हें 'इस्ट लाइट होटल' के कंपाउंड में खड़ी सफेद मारुति कार नजर आयी। इस कार पर डीडीडी—९८८० की नंबर प्लेट लगी थी। होटल मैनेजर से पुलिस को जानकारी मिली कि उक्त कार से आये लोग कमरा नंबर चार और दस में ठहरे हैं। दोनों कमरों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्चा था। पुलिस को देखते ही तीन पुरुषों में से दो युवकों ने जहर भरे कैप्सूल खा लिये। एक दैनिक पत्र में छपी खबर के अनुसार कैप्सूल खाते ही उनमें से एक युवक ने एक सबइंस्पेक्टर को यह कहते हुए एक झापड़ भी मारा था कि 'अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे ?' होटल के बाहर लाते समय ये दोनों युवक बेहोश हो गये।

पंजाब में आयी आतंकवादी हत्याओं की लहर के समानांतर उत्तर प्रदेश में भी आतंकवादियों को हत्या व लूटमार का दौर शुरू करके दहशत फैलानी है।

पाकिस्तान संबंध : हत्यारों की निशानदेही पर बरामद उन्नत किस्म के घातक विदेशी हथियार

बरेली पुलिस ने मुस्तैदी दिखायी और आनन-फानन इन दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने इन्हें बचा लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को सीट के नीचे ९ एमएम की एक पिस्टल तथा कार की दो फर्जी नंबर प्लेटें मिलीं।

पुलिस को तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अवतार सिंह डांग बताया। उनके साथ उनकी पत्नी दलवीर कौर और एक आठ वर्षीय पुत्र था। उनका कहना था कि वे दोनों युवक पीके शर्मा और राजविंदर उनके पड़ोसी थें और भाटिया लाज में रहते थे। ये युवक डांग परिवार को नैनीताल पहुंचाने जा रहे थे। डांग ने बताया कि उनकी बच्ची नैनीताल के एक स्कूल में पढ़ रही है। इन दोनों युवकों को डांग परिवार के साथ कड़े सुरक्षा घेरे में कानपुर लाया गया। भाटिया लाज के उनके कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को एक वीडियो कैसेट तथा कार की दो और फर्जी नंबर प्लेटों के अलावा कोई उल्लेखनीय सामान नहीं मिला। यह वीडियो कैसेट भाटिया लाज में ही रहनेवाले एक अन्य परिवार के बच्चे की 'बर्थ डे' पार्टी से संबंधित था।

पूछताछ : आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ तथा गुप्तचर अधिकारियों ने जब इनसे पूछताछ शुरू की, तो दोनों ने कुछ भी बताने से इनकार कर लिया, लेकिन अंततः पुलिस उनसे बहुत सारी बातें उगलवाने में कामयाब हो गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात पर फक्र कर सकती है कि उसने कत्याल के हत्यारों को हत्या के ६० घंटों के अंदर ही पकड़ लिया है, लेकिन इन दोनों ने जो जानकारियां उगलीं, उनसे उत्तर प्रदेश पुलिस स्तब्ध रह गयी। (देखिए बाक्स)

पूछताछ में पता चला है इन युवकों के पीकें शर्मा और राजविंदर नाम नकली हैं। पीके शर्मा का असली नाम सतविंदर उर्फ भोला और राजविंदर का असली नाम सुखबीर सिंह है। कत्याल की हत्या में इनके साथ दो और आतंकवादी कमरजीत सिंह और केवल सिंह भी शामिल थे। पुलिस इन दोनों की बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। भोला खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी जत्थे का प्रमुख प्रशिक्षक था तथा कमांडो फोर्स के तथाकथित जनरल लाभसिंह के बाद भोला दूसरे नंबर का जनरल था, जबकि सुखबीर सिंह उर्फ राजविंदर खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक सक्रिय सदस्य था।

भोला के पिता का नाम अमरीक सिंह है और वह जालंधर के अलीं मोहाल इलाके का निवासी है। भोला अमृतसर के खालसा कालेज का छात्र था और वहीं वह आतंकवादियों के संपर्क में आया। १९८ में वह दस महीनों तक जेल में भी रहा था। अमृतसर में ही उसकी मुलाकात पीलीभीत निवा सुखविंदर से हुई और आपरेशन ब्ल्यू स्टार के बा जब पंजाब में पुलिस का दबाव बढ़ गया, तो इ दोनों ने अपनी गतिविधियों का केंद्र उत्तर प्रदेश बना लियां। पीलीभीत में भोला के कुछ रिश्तेदा भी थे। हरजिंदर सिंह जिंदा को भोला ने तराई क्षे में पनाह भी दी थी। जिंदा ने तीन अ आतंकवादियों के साथ तराई क्षेत्र में अपने अड्डे ब लिये। जुलाई, १९८६ में इनके साथ कुछ औ आतकवादी निम्मा और सुक्खा भी आ मिले। आतंकवादी दिल्ली व पंजाब में वारदात कर तराई क्षेत्र में चले आते थे। सितंबर, १९८७ इन्होंने कानपुर और लखनऊ में भी अपने अड्डे ब लिये।

महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन : भोला जनर वैद्य के हत्यारों में शामिल था। यही नहीं लि माकन व अर्जुन दास की हत्या की योजना भी भो ने ही तैयार की थी। अमृतसर के डीआईजी अट और एक अन्य पुलिस अधिकारी एलसी मक्कड़

कत्याल हत्याकांड

चौंकानेवाले राज खुले

कांग्रेस-इ विधायक विलायती राम कत्याल की हत्या के इकबाली अभियुक्त इनामी आतंकवादी पीके शर्मा उर्फ सतविंदर सिंह उर्फ भोला ने उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के जो राज खोले और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ जो सामान बरामद किये, उनसे अनेक चौंकानेवाले तथ्य सामने आये हैं। ये तथ्य खुलासा कर देते हैं कि वीर बहादुर सिंह की सरकार आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में कितना अंधेरे में रही है? भोला और सुखबीर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पूछताछ हो रही है, क्योंकि पुलिस को भय है कि आतंकवादी इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पूछताछ में जो तथ्य सामने आये, वे इस प्रकार हैं:—

- उत्तर प्रदेश में आतंकवादी १९८४ से सक्रिय हैं।
- ६ अप्रैल को जब पुलिस कत्याल के हत्यारों को कानपुर में तलाश कर रही थी, तब भोला और सुखबीर बस से लखनऊ पहुंच गये थे, जहां विकास नगर में उन्होंने किराये पर एक फ्लैट ले रखा था। ७ अप्रैल को वे वापस आये। इस बीच कार भाटिया लाज के गैरेज में खड़ी रही। भोला मारुति कार से डांग परिवार के साथ बरेली पहुंचा था, जबकि सुखबीर बस से।
- भोला अपने आठ साथियों के साथ उत्तर प्रदेश में आया था।
- खालिस्तान कमांडो फोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल कहा जानेवाला भोला नैनीताल में अपना हेड क्वार्टर बनाये हुए था और उसकी शाखाएं उसने कानपुर व लखनऊ में स्थापित कर ली थीं।
- पुलिस को आतंकवादियों के सामानों में पाकिस्तान का बना एक फुट लंबा और दस इंच चौड़ा झोला मिला है, जिस पर उर्दू में 'तीस बोर के असली एक हजार' शब्द लिखे हैं। ऐसे ही झोलों में आतंकवादियों को पाकिस्तान से एक-एक हजार के पैकेट में गोलियां मिलती हैं।
- अनेक आतंकवादियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी से अपना रंगरूप बदल लिया है।
- भूतपूर्व थलसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वैद्य का हत्यारा हरजिंदर सिंह जिंदा तीन बार कानपुर आया था।
- कत्याल की हत्या में स्वचालित एमएम मशीन पिस्टल एवं एके-४७ रायफल जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया। वैसे, ये हथियार तो कुछ अरसा पहले तक भारतीय फौज के पास भी नहीं थे।
- आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश से अधिक सुरक्षित स्थान दूसरा नहीं है, क्योंकि यहां की पुलिस न केवल लापरवाह है, वरन बहुत लालची भी है। भोला मारुति कार से पुलिस को रुपए थमाते हुए सारे चेक पोस्टों से साफ बच निकला था।
- कत्याल के हत्यारों जैसे पचास खतरनाक आतंकवादी उत्तर प्रदेश में अपने अड्डे बना चुके हैं।
- कानपुर के ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में हुई लूट की वारदात के लिए पुलिस राजू भटनागर और उसके साथियों की तलाश कर रही थी, जबकि पौने दो लाख रुपए की लूट इसी भोला ने अपने साथियों के साथ की थी। इस लूट में जो छह फुटा जवान था, उसका नाम केवल सिंह है, जबकि पुलिस उसे राजू भटनागर का साथी लक्ष्मीनारायण समझ रही थी। कत्याल की हत्या में प्रयुक्त मारुति कार इसी बैंक की लूट से प्राप्त धन से खरीदी गयी थी।
- आतंकवादी लूट का सारा पैसा स्वर्ण मंदिर में दे देते हैं, बदले में उन्हें तनख्वाह मिलती है। भोला ने बताया कि उसे १५ हजार रुपए माहवार मिलते हैं।
- आतंकवादियों को हथियार स्वर्ण मंदिर से मिलते हैं और वहां पाकिस्तान से हथियार पहुंचते हैं। ये हथियार विभिन्न धार्मिक स्थानों पर छिपाकर रखे जाते हैं और जरूरत पड़ने पर वहां से निकाल लिये जाते हैं।
- उत्तर प्रदेश में सक्रिय आतंकवादी 'ऊपर अर्थात खालिस्तान कमांडो फोर्स के आदेश से आये हैं। उन्हें हिदायत मिली है कि ये लोग उत्तर प्रदेश को अपना निशाना बनायें।
- किच्छा (नैनीताल) और काशीपुर की बैंक डकैती इन्हीं आतंकवादियों का काम था। काशीपुर में ये बैंक तो नहीं लूट सके थे, लेकिन एक आदमी मारा गया था और चौकीदार घायल हुआ था।
- उत्तर प्रदेश में खालिस्तान कमांडो फोर्स के अलावा बब्बर खालसा और खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी के आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय हैं, जिनके मुखिया क्रमशः लाभ सिंह, सुखदेव सिंह बब्बर और सरदार पुत्तल सिंह हैं।
- तराई क्षेत्र में भिंडरांवाले टाइगर फोर्स के भी कुछ सदस्य सक्रिय हैं।
- ये सभी आतंकवादी गिरोह ४५ कारबाइन, ए के-४७ चाइनीज आटोमैटिक रायफल, ३०-ओजी कमांडो मिलेट्री रायफलें, नंबर-४५ स्टेनगन, .४५५ बोर के रिवाल्वर, ९ एमएम स्टेनगन और हैण्ड ग्रेनेडों का इस्तेमाल करते हैं।

हत्या करनेवालों में भी भोला शामिल था। भोला ने स्पष्ट स्वीकार किया कि जालंधर के लालडू बस हत्याकांड में भी उसने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी तरह पटियाला में एक पुलिस अधिकारी के पुत्र की हत्या के साथ ही उसने पंजाब में ११ बैंकों को लूटा था।

भोला ने बताया, "मैंने अपने दो साथियों कमरजीत सिंह और केवल सिंह के साथ वर्ष १९८४ में पाकिस्तान में हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हमारे साथ प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले पंजाब के पांच सौ से ज्यादा लोगों में हरजिंदर सिंह जिंदा भी था। प्रशिक्षण प्राप्त कर हमने पंजाब और पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दीं। एक बार मुझे और जिंदा को पंजाब पुलिस ने हमारे तीन अन्य साथियों के साथ पकड़ लिया था। हम पांचों को पुलिस बंदोबस्त के बीच अमृतसर कचहरी में रखा गया था। तभी हमारे एक दर्जन दूसरे साथी दो कारों से कचहरी आ पहुंचे तथा पुलिस पर ताबड़-तोड़ गोलियां चलाकर, हमें उनके कब्जे से छुड़ा लिया।"

लेकिन कत्याल हत्याकांड और हत्याकांड के बाद मारुति कार से कानपुर से बाहर निकल जाने का जो विवरण इन दोनों आतंकवादियों ने दिया उसने तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर एक तरह से कालिख ही पोत दी।

हत्या का विवरण: कत्याल की हत्या की योजना भोला, सुखवीर, कमरजीत और केवल सिंह ने बड़ी चतुराई से बनायी थी। उन्हें पता था कि हत्या के तत्काल बाद कड़ी छानबीन शुरू हो जायेगी। हत्या के एक दिन पहले अर्थात ४ अप्रैल की दोपहर वे चारों मारुति कार से 'कानपुर आटो ट्रैक्टर गैराज' गये। जहां उन्होंने अगले दिन के लिए कार की सर्विसिंग की बुकिंग करायी और टोकन ले लिया। हत्या के तत्काल बाद जब कारों की कड़ी तलाशी शुरू हो गयी, तो यही टोकन आतंकवादियों के काम आया। पुलिस अधिकारी इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों के अनुसार हत्या के एक घंटे बाद ही कर्नलगंज थाने के पास पुलिस ने जब इनकी कार रोकी, तो ड्राईविंग सीट पर बैठे भोला ने चैकिंग करनेवाले दरोगा को सौ रुपए का एक नोट थमाते हुए गाड़ी सर्विसिंग का टोकन भी दिखाया। दरोगा ने रुपए लेकर उन्हें जाने दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि दरोगा ने एक सिपाही को इस कार के साथ यह दरियाफ्त करने भेजा था कि क्या वाकई इस गाड़ी की सर्विसिंग होने की बात सच है? लेकिन सवाल उठता है कि जब हर गाड़ी की तलाशी लेने के आदेश थे, तो इनकी मारुति कार की तलाशी क्यों नहीं ली गयी?

सर्विसिंग कराने के बाद शाम चार बजे भोला और सुखबीर भाटिया लाज आये। उन्होंने वहीं खाना खाया। उनकी कार लाज के गैराज में खड़ी रही। रात लगभग आठ बजे भोला अपने पड़ोसी डांग के यहां गया, तो पता चला कि वह अपनी बेटी से मिलने नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। भोला को लगा कि कार सहित कानपुर से बाहर

सोवियत संघ के उत्सव भारत 1987-88

सोवियत संघ

सचित्र मासिक पत्रिका

नये जीवन का निर्झर

विश्व की बीस भाषाओं में प्रकाशित यह पत्रिका अपने पाठकों को सोवियत जीवन के सभी पहलुओं से, सोवियत जनता की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी और काम से परिचित कराती है ।

सोवियत पुरुषों और महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं तथा क्रियाकलापों में नये खुलेपन के वातावरण को प्रतिबिम्बित करती है ।

एक वर्ष २५ रुपये
तीन वर्ष ५० रुपये

सोवियत संघ

साथ में २५/५० रुपये डिमांड ड्राफ्ट/मनी आर्डर रसीद संलग्न है

नाम ______________________

पता ______________________

____

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये

मैगज़ीन सेन्टर
एम सी डी बिल्डिंग
नं. २, दूसरी मंज़िल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
नई दिल्ली-११००५५

राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि.
चमेलीवाला मार्केट, एम.आई.रोड
जयपुर–३०२००१

बिरा शताब्दि
५२-बि, पार्क स्ट्रिट
कलकत्ता-७०००१६

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
५-ई रानी झांसी रोड
नई दिल्ली-११००५५

03

निकलने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता, लेकिन वह उसी दिन कानपुर से नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि चौकसी कड़ी थी और पकड़े जाने का पूरा अंदेशा था। इसलिए उसने डांग को दो दिन बाद अर्थात ७ अप्रैल को अपने साथ कार से नैनीताल चलने के लिए राजी कर लिया। ७ अप्रैल की शाम करीब चार बजे भोला अवतार सिंह डांग उनकी पत्नी और बच्चे को कार में बिठाकर नैनीताल के लिए रवाना हो गये। रास्ते में जाजमऊ पुल, इंटौंजा और सीतापुर में उनकी कार पुलिस द्वारा रोकी गयी, तो भोला ने फर्जी कागजात दिखा दिये। लखनऊ के आलमबाग इलाके में जब एक दरोगा ने कार रोककर तलाशी लेनी चाही, तो भोला के अनुसार पचास रुपए का नोट थमाने पर उस दरोगा ने भोला को सेल्यूट किया और कार को बाइज्जत जाने दिया। इस प्रकार कत्याल हत्याकांड के दो अभियुक्त इस तरह न केवल कानपुर, बल्कि लखनऊ से भी निकलने में कामयाब हो गये। अन्य दो अभियुक्त केवल सिंह और कमरजीत सिंह भी इसी तरह कानपुर से निकल गये हों, तो कोई आश्चर्य नहीं, जबकि पुलिस का दावा है कि वे कानपुर में ही कहीं छिपे हुए हैं। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी कारों की मुस्तैदी से तलाशी नहीं ली, यदि तलाशी ली होती, तो बरेली में भोला की मारुति कार से जो हथियार बरामद हुआ वह कानपुर के जाजमऊ पुल पर बरामद हो सकता था।

हथियारों का जखीरा: कहां तो पुलिस का दावा था कि कानपुर में कोई आतंकवादी अड्डा नहीं है, वहीं ११ अप्रैल की रात लगभग दो बजे पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर कानपुर के काकादेव इलाके में स्थित मकान नंबर—११७/४ में छापामार कर एक एके-४७ चायनीज एसाल्ट रायफल, एक ओजी कमांडो-अमरीकन रायफल, एक ९-एमएम की थर्टी माउजर पिस्टल तथा एक ४५५ बोर की विदेशी रिवाल्वर के साथ ४३४ विदेशी कारतूस भी बरामद कर लिये। तलाशी के दौरान पुलिस को उस मकान के एक कमरे में स्वर्गीय कत्याल का बैग भी मिला, जिसमें उनका विधानसभा परिचय पत्र, चाबियां तथा कुछ जरूरी कागजात थे। इसके अतिरिक्त यूएमवाई-५०० तथा डीडीसी-२१९३ नंबर की नंबर प्लेटें भी बरामद हुईं। इसी कमरे में कानपुर आरटीओ की रबर स्टैंप, फर्जी नाम के कुछ लाइसेंस और आरटीओ के फर्जी हस्ताक्षर युक्त सादे लाइसेंस भी पाये गये। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि जिस मकान से हथियार बरामद हुए थे, वहां कत्याल का निजी बैग कैसे पहुंचा, जबकि वह कत्याल की स्कूटर की डिक्की में था और डिक्की पर ताला लगा था। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद भोला ने डिक्की से यह बैग इसलिए निकाल लिया था, जिससे वह कत्याल के विधानसभा परिचय पत्र को काम पूरा होने के प्रमाणस्वरूप अपने 'हाईकमान' को भेज सके। लेकिन पुलिस का यह तर्क आसानी से गले नही उतरता।

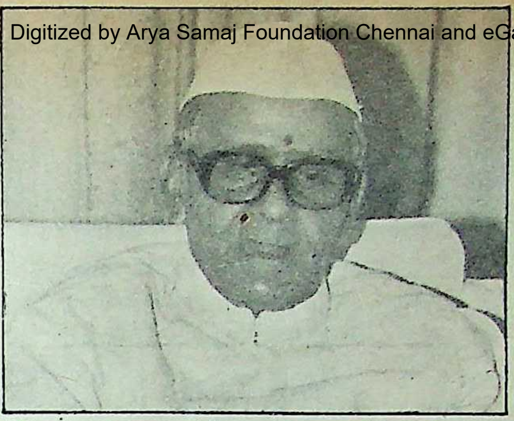

मैं क्या कर सकता हूं ? : राज्य गृह मंत्री गोपीनाथ

पुलिस को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर और अधिक हथियार छुपे होंगे, यही वजह है कि गुप्तचर विभाग का विशेष पूछताछ दस्ता भोला और सुखबीर को आगे पूछताछ के लिए बरेली ले गया है। पंजाब से आये विशेष पुलिस दल ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंजाब से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गये ३६ आतंकवादियों की फोटो सहित सूची दी है। जिससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अनेक खूंख्वार आतंकवादी घुस आये हैं, और वे सिर्फ कत्याल की ही हत्या करनें नहीं आये थे। पाकिस्तान से इन आतंकवादियों का दिसंबर, १९८७ में जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार पंजाब में आयी आतंकवादी हत्याओं की लहर के समानांतर उत्तर प्रदेश में भी इन्हें हत्या व लूटमार का दौर शुरू करके दहशत फैलानी है, खासकर उन जगहों पर जहां १९८४ में श्रीमती गांधी की हत्या के प्रतिक्रियास्वरूप दंगे भड़के थे। कानपुर पर तो उनकी विशेष नजर है, क्योंकि यहां न केवल सिखों की संख्या अच्छी-खासी है, बल्कि यहां आयुध कारखाना भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुखबीर और भोला से और भी बहुत सी बातें उगलवाने के लिए प्रत्यनशील है। इन दोनों के अलावा पुलिस ने सात अन्य लोगों को भी आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें भाटिया लाज और काकादेव का मकान मालिक भी शामिल है। पुलिस को हत्याकांड में शामिल केवल सिंह व कमरजीत सिंह के अलावा निर्मल सिंह उर्फ निम्मी की भी तलाश है। पुलिस एक खूबसूरत लड़की को भी तलाश रही है जो अकसर भोला के साथ घूमती हुई देखी गयी थी।

बहरहाल, कत्याल के हत्यारों को पकड़ लेने के बावजूद इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद से लड़ने की अक्षमता को पूरी तरह उजागर कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्त्सना की है। देखना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ आये आतंकवादियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में फैले आतंकवादियों के जाल को किस सीमा तक तोड़ने में कामयाब हो पाती है?

—कानपुर से अजय कुमार और निशीथ जोशी

छाया: राजेंद्र कुमार

यदि एक राष्ट्र-प्रेमी सिख ने सुराग न दिया होता, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बस की बात नहीं थी कि वह अपराधियों तक पहुंच जाती।

जैट और बोस्की
सिर्फ क्वालिटी पसन्द लोगों के लिये।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS

तैयब हुसैन ने पाला ऐसे बदला

विधान सभा में लोकदल के विरुद्ध घोर गर्जना करने वाले मेव नेता चौ० तैयब हुसैन लोकदल में शामिल होकर मंत्री-पद पा गये हैं। बकौल तैयब साहब कि भजनलाल जैसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के कारण कांग्रेस में मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति का रहना दूभर हो गया है। उन्होंने कांग्रेस भजनलाल के चलते छोड़ी है या चौधरी देवीलाल ने आगामी संसदीय उपचुनाव को देखते हुए उन्हें अपने पाले में मिला लिया है? इस 'दलबदल' के बाद हरियाणा की राजनीति ने क्या मोड़ लिया है?

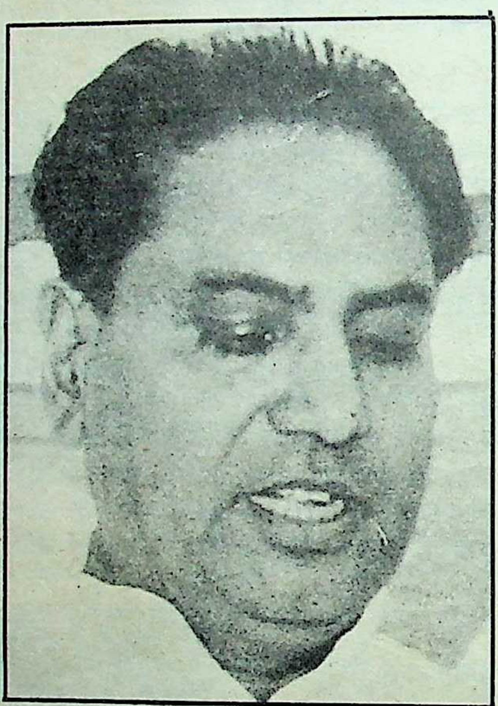

रंग बदलने में माहिर: चौ० तैयब हुसैन

कल तक विधानसभा के भीतर और बाहर चौधरी देवीलाल की लोकदल-भाजपा सरकार के खिलाफ गरजने वाले प्रमुख मेव नेता चौधरी तैयब हुसैन १० अप्रैल को अचानक कांग्रेस छोड़कर लोकदल में शामिल हो गये तथा दूसरे ही दिन देवी लाल ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है! मई के अंतिम सप्ताह में हरियाणा की फरीदाबाद और सिरसा (सुरक्षित) संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव होने ही हैं। चौधरी तैयब हुसैन की तावडू विधानसभा सीट फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। गत वर्ष जून के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल की लहर के बावजूद बतौर गृहमंत्री पुलिस की मदद से वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे थे। जाहिर है, देवीलाल ने संसदीय उपचुनाव को मद्देनजर रख कर तैयब हुसैन को अपने साथ करना आवश्यक समझा है। मेव जाति पर उनका असर है और वह मेव पंचायत के चौधरी भी हैं।

चौधरी तैयब हुसैन के दलबदल से कांग्रेस को धक्का लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इस बजट सत्र में ही उन्हें सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। विधानसभा में जब भी केन्द्रीय कृषिमंत्री भजनलाल का नाम उछला, उन्होंने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम इस तरह नहीं घसीटा जाना चाहिए। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेसाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने जोर देकर कहा कि भजनलाल जैसे 'भ्रष्ट' राजनीतिज्ञ के कारण ही वह कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जब तक कांग्रेस में ऐसे भ्रष्ट लोग रहेंगे, तब तक उन (तैयब हुसैन) जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि अब तैयब हुसैन को भजन लाल देश का सबसे बड़ा दलबदलू करार दे रहे हैं। वैसे स्वयं भजन लाल का अपना कीर्तिमान काफी ऊंचा है। १९८० में वह पूरी की पूरी जनता सरकार लेकर कांग्रेस में शामिल हो गये थे।

विपक्षी एकता के संदर्भ में चौधरी देवीलाल अकसर कहते हैं कि पार्टियां नेता नहीं बनातीं, वरन नेता पार्टियां बनाते हैं। अगर उनके कथन को ब्रह्म वाक्य माना जाये, तो हरियाणा में पार्टियों का नहीं, वरन झंडे वाली कार, आगे-पीछे घूमते सशस्त्र गार्ड का ज्यादा महत्व होता है। वह तो चौधरी देवीलाल थे, जो बरसों विपक्ष में रहकर भी अपनी राजनीति चलाते रहे और जनता पर से अपने तिलस्म को नहीं टूटने दिया। उनका तरीका दूसरा था, उन्होंने तथा उनके साथियों ने कभी किसी सरकार का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। जब भी चाहा और जो भी चाहा, अधिकारियों के सिर पर चढ़कर उनका गला पकड़कर करा लिया। ऐसी राजनीति करना सबके बस की बात नहीं है। कम-से-कम सत्ता-सुख के आदी हो चुके कांग्रेसी तो जमीन की ऐसी राजनीति हरगिज नहीं कर सकते।

मेवों के वोट: कहा जा सकता है कि चौधरी तैयब हुसैन को अपनी ओर मिलाते समय चौ० देवीलाल की निगाह फरीदाबाद के संसदीय उपचुनाव पर होगी, क्योंकि वहां दस लाख के लगभग मतदाताओं में ढाई-तीन लाख अकेले मेव हैं जो चौ० तैयब हुसैन के साथ-साथ शिक्षा मंत्री खुर्शीद अहमद तथा पशुपालन राज्यमंत्री अजमद खान (ये दोनों भी मेव नेता हैं) के सीधे असर में होंगे। इन तीनों मेव नेताओं के विधानसभा क्षेत्र क्रमश: तावडू, नूह और फिरोजपुर झिरका भी इसी फरीदाबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आते हैं। चौ० देवीलाल इस सीट के लिए किसी नवोदित मेव नेता को लड़ाने का विचार रखते हैं, कि जो चौ० तैयब हुसैन के बेटे जाकिर हुसैन भी हो सकते हैं। हरियाणा के जाट-बहुल क्षेत्र में जाटों की भांति मेवात क्षेत्र में मेवों का आधिपत्य है। जाटों की भांति वे भी अपने वोट तो देते ही हैं, बोगस वोट भी धड़ल्ले से डालते हैं। इन परिस्थितियों के रहते फरीदाबाद की सीट तो अभी से चौ० देवीलाल की झोली में मान ली जानी चाहिए।

चौ० देवीलाल ने वाल्मीकियों, राजपूतों और गूजरों को भले ही अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व न दिया हो, लेकिन मेवात से चुने गये तीनों विधायकों को जरूर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है, वरना एक या बहुत हुआ तो दो मंत्री ही पिछले मेवात क्षेत्र से लिये जाते रहे हैं।

एक और खास बात। मेवात क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में चौ० तैयब हुसैन और चौ० खुर्शीद अहमद एक दूसरे के कटु आलोचक और प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। दोनों ने समय और परिस्थितियों के अनुसार दल बदले हैं, लेकिन एक ही दल में कभी नहीं रहे। जून १९८६ में जब चौ० बंसीलाल अचानक मुख्यमंत्री बनकर हरियाणा आये, तो चौ० तैयब हुसैन (उस समय कांग्रेस-ज के विधायक) कांग्रेस में चहलकदमी करते हुए आ गये और गृहमंत्री बना दिये गये। उस समय तक चौ० खुर्शीद अहमद हारे हुए विधायक के रूप में कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तैयब हुसैन कांग्रेस में भरती हो गये हैं, तो वह चौ० देवीलाल के साथ जा बैठे और तब अपने पूरे वेग से दौड़ रही संघर्ष समिति के सेनानी बन गये।

जून १९८७ के विधानसभा चुनावों में पूरी संभावना थी कि चौ० तैयब हुसैन और चौ० खुर्शीद अहमद में आमने-सामने की टक्कर होगी, लेकिन अचानक गुल खिला और चौ० खर्शीद अहमद की ओर सरक गये तथा तावडू में चौ० देवीलाल का

एक पुराना चेला टिकट मांगता रह गया, पर चौ० खुर्शीद अहमद ने किसी नौसिखिये को टिकट दिलाकर चौ० तैयब हुसैन की जीत पक्की कर दी। जबरन वोट डालने की घटनाओं के बावजूद चौ० देवीलाल का चेला निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए भी दूसरे स्थान पर रहा और चौ० तैयब हुसैन अपनी सीट बचा गये।

चौधराहट का सवाल: अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में मेवात में किसकी चौधराहट चलेगी, यह कहना कठिन है। लेकिन अगर चौ० तैयब हुसैन के पुत्र को संसदीय उपचुनाव का टिकट मिल गया, तो निश्चय ही चौधराहट में वह बाकी दो से आगे निकल जायेंगे। चौ० तैयब हुसैन और चौ० खुर्शीद अहमद कांग्रेस और विपक्ष में आते जाते रहे हैं, लेकिन चौधरी अजमद खान जनता पार्टी में रहे अथवा लोकदल में या निर्दलीय होकर चुनाव अखाड़े में अपने सींग फंसाये रहे, पर कांग्रेस में कभी नहीं गये। प्रदेश लोकदल के पूर्वाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य चौ० ओम प्रकाश चौटाला तैयब साहब और खुर्शीद मियां की अपेक्षा चौ० अजमद खान को मेवात में स्थापित करने के पक्षधर कहे जाते हैं। उनका मानना है कि मेव नेताओं की अपेक्षा अजमद खान अधिक भरोसेमंद हैं।

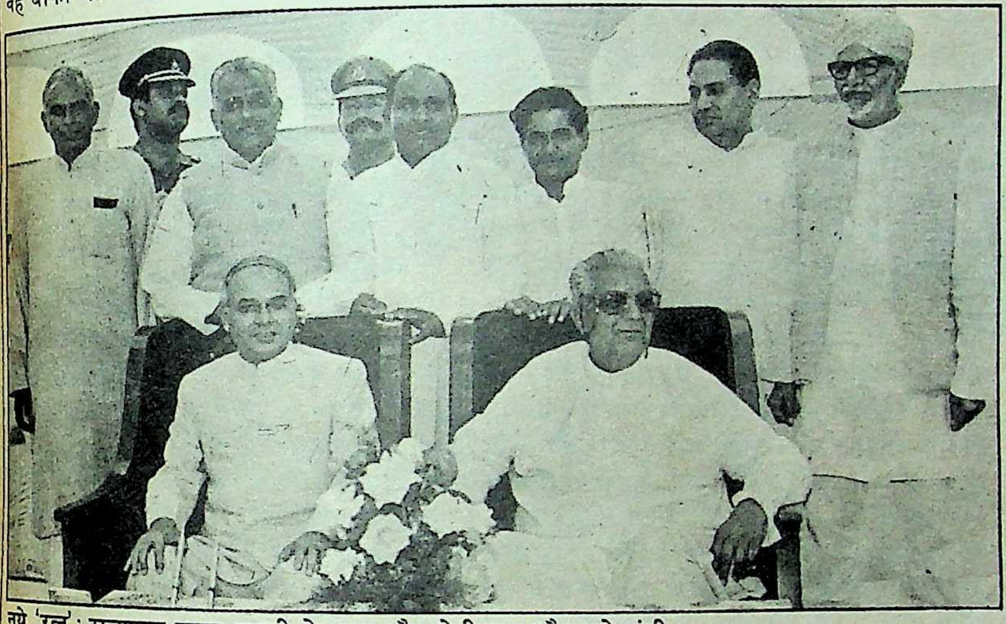
नये 'रत्न': राज्यपाल एचए बरारी के साथ चौ० देवीलाल और नये मंत्री

११ अप्रैल को जब तैयब साहब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो अजमद खान बहुत दुखी नजर आ रहे थे। लेकिन खुर्शीद अहमद अपना दुख छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा चहक रहे थे। चूंकि हरियाणा कांग्रेस में अब दम नहीं रहा, वरना खुर्शीद साहब से कलाबाजी की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन अगर कांग्रेस में दम होता, तो तैयब साहब पाला ही क्यों बदलते?

सूत्रों का कहना है कि चौ० देवीलाल और चौ० तैयब हुसैन के मध्य सुलह-वार्ता विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से जारी हुई। बीच में पत्रकारों को भनक लगी, तो उन्होंने तैयब साहब से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तैयब साहब ने कहा कि डोरे तो डाले जा रहे हैं, लेकिन उनका दलबदल का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही विधानसभा में उन्होंने बजट, कर्जामाफी की डटकर आलोचना करनी शुरू कर दी और कालोनाइजर्स कांड पर श्वेत पत्र जारी करने, इसकी न्यायिक जांच, मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष में आये चन्दे, चन्दा देने वालों के नाम प्रसारित करने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए उसे भंग करने की मांग करनी शुरू कर दी। यह सब तो जाहिरा तौर पर हो रहा था, लेकिन परदे के पीछे चौ० तैयब हुसैन तो दलबदल के लिए राजी हो गये थे, पर चौ० देवीलाल ने उन्हें एक विधायक और लाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी, ताकि पांच में से दो विधायक बिना इस्तीफा दिये लोकदल में आ सकें।

तैयब हुसैन ने अपना हाथ छछरौली के मुस्लिम गूजर विधायक मुहम्मद असलम खान पर रखा। यहां भी जाहिरा तौर पर असलम यही कहते रहे कि तैयब साहब उनके पिता तुल्य हैं, जैसा वह कहेंगे, असलम करने को तैयार हैं। लेकिन पाला बदलने के लिए निर्धारित ८ अप्रैल को असलम साहब ने एक दिन की मोहलत और मांग ली। तब तक हर आदमी जान गया था कि दलबदल होने जा रहा है और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यह भी आम चर्चा का विषय बन गया था कि तैयब हुसैन का मंत्री बनना तय है। असलम, जोकि पहली बार विधायक चुने गये हैं, उन्हें उनके मित्र-हितैषियों ने समझाया कि इस सौदेबाजी में तैयब मियां तो झंडेवाली कार और कोठी पा रहे हैं, तुम्हें दलबदल की क्या कीमत मिलेगी?

६ अप्रैल की रात तक दोनों चौधरियों ने व्यग्रता से असलम के संदेशों की प्रतीक्षा की। १० तारीख की सुबह उन्हें खोजने की कोशिश भी की गयी, लेकिन वह हाथ नहीं लगे। इधर मुख्यमंत्री जो चार दिन पहले तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना से इनकार करते थे, ११ अप्रैल को मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा भी कर चुके थे। वैसे कहकर मुकर जाना चौ० देवीलाल की आदत में शुमार है, लेकिन अब बुढ़ापे में ऐसा करने से उनकी हंसाई होती। परिणामतः मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि तो वही रखी गयी, लेकिन तैयब साहब को अकेले ही आना पड़ा, जिसके कारण उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देने की औपचारिकता निभानी पड़ी। छह माह के भीतर उपचुनाव लड़कर उन्हें अपना दलबदल पहलू सार्थक सिद्ध करना होगा।

सार्वजनिक रूप से चौ० देवीलाल कहा करते थे कि कांग्रेस को पांच सीटें भी उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध करके दिलवायी हैं, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई कांग्रेसी विधायक न हुआ, तो किसकी ओर मुखातिब होकर कांग्रेस की कलई खोलेंगे। दूसरे, वह हर सभा में कहा करते थे कि उन्होंने हरियाणा से कांग्रेस का जनाजा निकलवा दिया है। कांग्रेस के पांच विधायकों में चार उस जनाजे को कंधा देने वालों में हैं तथा एक महिला, आदमपुर से निर्वाचित भजनलाल की पत्नी जसमा देवी, रोने वालों में से हैं, जनाजे के साथ-साथ।

यह जनता में कहने की बात थी। परदे के पीछे उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जसमादेवी को छोड़कर (क्योंकि वह दलबदल तब तक नहीं कर सकतीं, जब तक उनके पति कांग्रेस में हैं) शेष सब उनके पाले में आ जायें। लोकदल का टिकट कट जाने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नारायणगढ़ (जिला अम्बाला) से विजयी गूजर नेता जगपाल सिंह चौधरी जब गूजर कोटे से मंत्रिमंडल में अपना स्थान मांगने चौधरी देवीलाल के पास गये, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि कांग्रेस के दोनों गूजर विधायकों, असलम साहब तथा मेवला महाराजपुर के महेन्द्र प्रताप सिंह को भी तोड़ लाओ, तो मैं तुम्हारे दावे पर विचार कर सकता हूं।

जगपालसिंह चौधरी ऐसी कसरत का औचित्य नहीं समझ पाये फिर भी उन्होंने दोनों को पटाने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिल पायी। असलम मियां पहले तो ना-नुकुर करते रहे, लेकिन बाद में कहने लगे कि चौ० तैयब हुसैन जो आज्ञा देंगे, वह वैसा ही करेंगे। चौ० तैयब हुसैन तो दीवार फांद गये, लेकिन असलम अभी भी वहीं बैठे हैं। महेन्द्र प्रातप सिंह ने दलबदल करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मंत्री क्या मुख्यमंत्री पद का लालच भी उन्हें बहका नहीं सकता है।

कांग्रेसी हलकों में कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरियाणा के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपेक्षा करके भजनलाल के हवाले हरियाणा कांग्रेस कर दी है, जिससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गयी है। भजनलाल को नापसंद करने वालों ने राजीव गांधी की आंखें खोलने के उद्देश्य से यह करतब कराया। चूंकि चौधरी तैयब हुसैन को चौधरी बंसीलाल से जोड़ा जाता है (वह रहे भी उन्हीं के वफादार), अतः इस दलबदल को चौधरी बंसीलाल का आशीर्वाद बताया जा रहा है।

—विशेष प्रतिनिधि

लतीफ कैसे रिहा हुआ ?

१२ मार्च, १९८८ को प्रधानमंत्री राजीव गांधी दांडी यात्रा का शुभारंभ करने अहमदाबाद आये थे। उसके अगले दिन अहमदाबाद की अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जानेवाला अब्दुल लतीफ अब्दुल बहाव शेख जेल से रिहा हो गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पायी। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं कि लतीफ कहां गायब हो गया। इस घटना की जांच अपराध शाखा के एसपी श्री रबारी कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि जेल के दो अफसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिये। ये अफसर इतने घबड़ाए हुए हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानतें ले ली हैं।

पुलिस के रिकार्ड के मुताबिक कई कांग्रेसी राजनीतिज्ञ लतीफ के साथी हैं और यह आम धारणा है कि लतीफ की मदद करने में इंका के भूतपूर्व विधायक मोहम्मद हुसैन बारेलिया और सांसद रऊफ वलीउल्लाह जैसे लोगों ने अहम भूमिका निभायी थी। पुलिस नहीं चाहती थी कि लतीफ उसके शिकंजे से बच निकले, इसीलिए १९८५ के बाद वह लतीफ को एक-के-बाद एक कई आरोपों में बारबार गिरफ्तार करती रही है। वह जेल से जैसे ही एक मामले में बरी होता, पुलिस उसे फिर से अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लेती। लेकिन इस बार पुलिस को शिकायत है कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने 'पासा' (पीएएसए) के सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर लतीफ को सारे आरोपों से बरी कर जेल से छोड़ने के आदेश दे दिये और पुलिस को इसकी जानकारी लतीफ के रिहा होकर फरार हो जाने के बाद दी गयी। आखिर गृह विभाग शराबबंदी कानून के उल्लंघन, हत्या, दंगे-फसाद आदि के ५० से अधिक मामलों में वांछित लतीफ को पुलिस से क्यों बचाना चाहता है? क्या राजीव गांधी की दांडी यात्रा समारोह के निमित्त अहमदाबाद यात्रा का लतीफ की रिहाई से कोई संबंध है? सरसरी तौर पर देखने से ऐसा नहीं लगता, लेकिन जानकार लोग दावे के साथ इन दोनों के बीच संबंध जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अहमदाबाद में कांग्रेस-इ का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लतीफ के साथ कांग्रेस-इ के 'प्रेम संबंध' होने जरूरी हैं। इस समय अहमदाबाद नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है और तमाम बदनामी एवं विरोध के बावजूद जनवरी, १९८७ में हुए नगर निगम के चुनावों में लतीफ ने पांच क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा था और सभी स्थानों पर विजयी हुआ था। कांग्रेस-इ खेमे की धारणा है कि लतीफ के खिलाफ पुलिस की चल रही सतत कार्यवाही से अहमदाबाद का मुसलमान कांग्रेस-इ के खिलाफ होता जा रहा है। यहां तक कि अहमद पटेल को प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष बना देने का भी मुसलमानों पर कोई बहुत अनुकूल असर नहीं पड़ा है।

३६ वर्षीय लतीफ शेख पुलिस की नि भले ही घोर अपराधी हो, लेकिन वह अहमदा मुसलमानों का 'मसीहा' समझा जाता है। दरियापुर में उसका एक छापाखाना है, पुलिस के अनुसार उसका असली धंधा अवैध शराब की बिक्री है। गुजरात में मद्य निषेध इसलिए शराब की अवैध बिक्री से उसे लाखों कमायी होती है। बंबई के नामी अपराधियों अयूब और आलम जेब से उसके करीबी संबंध हैं। १९८५ के आरक्षण-विरोधी आंदोलन के भड़के सांप्रदायिक दंगों में लतीफ ने प्रमुख भू निभायी थी। मुसलमान उसे 'पटेल' नाम से पु थे। जब दंगों के दौरान रिबेरो (अब पंजा पुलिस चीफ) पुलिस चीफ बनाये गये, तो लती शामत आ गयी थी। रिबेरो के बाद तैना आईजीपी मनमोहन सिंह, पुलिस आयुक्त सिन् लतीफ से सख्ती से पेश आते रहे। लेकिन कहा है कि यह लतीफ के ऊंचे संपर्कों का ही कमाल है इतने अधिक आरोपों और बारंबार गिरफ्तार के बावजूद उसे अभी तक किसी मामले में सजा हुई।

लतीफ के पास धन है और मुसलमानों थोक वोट उसके पास हैं। चर्चा है कि इसी कारण बार उस पर कांग्रेस-इ सरकार की कृपा हो ग ११-१२ मार्च को जब अहमदाबाद का सारा पु महकमा राजीव गांधी की सुरक्षा और दांडी समारोह की व्यवस्था में जुटा था, तो कहा जा कि दिल्ली में आये चिदंबरम जैसे अति मह व्यक्तियों के निर्देश पर पासा (पीएएसए) सलाहकार मंडल ने लतीफ के मामले पर तु फुरत विचार करके उसे सभी आरोपों से बरी दिया। पुलिस को खबर तक नहीं हुई और ल उसके हाथों से बहुत दूर चला गया।

सोलंकी फिर से तख्तनशीन होंगे !

गुजरात में भड़के दंगों को नियंत्रित करने में असफल रहने और आरक्षण विरोधी उग्र आंदोलन के कारण माधव सिह सोलंकी को १९८५ में जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो सोलंकी ने कांग्रेस-इ की नीतियों की आलोचना करते हुए राजीव गांधी को एक कठोर पत्र लिखा था। तभी कयास लगाया गया था कि सोलंकी के लिए कांग्रेस में कोई ठौर नहीं है। जो लोग सोचते थे कि उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जायेगा, वे भी नाराज हो चले थे। यहां के गुजराती दैनिक 'गुजरात समाचार' ने भी सोलंकी को बदनाम करने का ऐसा अभियान छेड़ा था कि राजीव सरकार के खिलाफ आंदोलनरत राजा वीपी सिंह ने भी उन्हें अपने साथ जोड़ने की हिम्मत नहीं दिखायी, यही बात सोलंकी के लिए वरदान बन गयी। वह कांग्रेस-इ में बने रहे और राजीव गांधी ने हाल ही राज्यसभा के लिए सोलंकी के प्रबल विरोधी योगेंद्र मकवाना का टिकट काटकर सोलंकी को राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया, जबकि मकवाना १७ साल से राज्य सभा के सदस्य थे, आठ साल तक केंद्र में मंत्री रह चुके थे और उन्हें राज्यसभा का टिकट देने की सिफारिश खुद मुख्यमंत्री चौधरी अमर सिंह ने की थी। इससे यह तो संकेत मिलता ही है कि सोलंकी केंद्र में मंत्री बनाये जायेंगे, साथ ही गुजरात में मुख्यमंत्री अमर सिंह और प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष अहमद पटेल के बीच जिस तरह की आपसी जंग छिड़ी हुई है, उससे यह भी संकेत मिलता है कि उन्हें आम चुनावों के बहुत पहले ही गुजरात की गद्दी एक बार फिर सौंप दी जायेगी।

वैसे तो अहमद पटेल और मुख्यमंत्री अ सिंह चौधरी के बीच अनबन का इतिहास का पुराना है, लेकिन दिसंबर १९८७ में मुख्य अमर सिंह चौधरी ने रफालेश्वर के पशु शिविर में छापा मरवाकर अहमद पटेल को बद करने की जो कोशिश की, उससे कांग्रेस-इ संगठ बदनाम हुआ, क्योंकि अहमद पटेल सूखा समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी थे और पशुराहत शि में घपले हुए थे। दोनों के बीच अनबन ऐसी ब स्वयं राजीव गांधी को समझौता कराना पड़ा। समर्थक विधायक इससे संतुष्ट नहीं हुए और उ अमर सिंह को हटाने के लिए दस्तखत अभियान दिया। इस सबसे अमर सिंह की स्थिति कमजो रही है। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है माधव सिंह सोलंकी को गुजरात की बागडोर दी जायेगी, क्योंकि यह सोलंकी का ही बलबूता कि १९८५ के चुनावों में १८० सदस्यों गुजरात विधानसभा में कांग्रेस-इ के १४७ पहुंचे थे। शायद उनकी यह खूबी उन्हें फिर गुजरात का सिंहासन दिलवा सकती है।

—चौला

साक्षात्कार/राज बब्बर

अमिताभ का विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य है

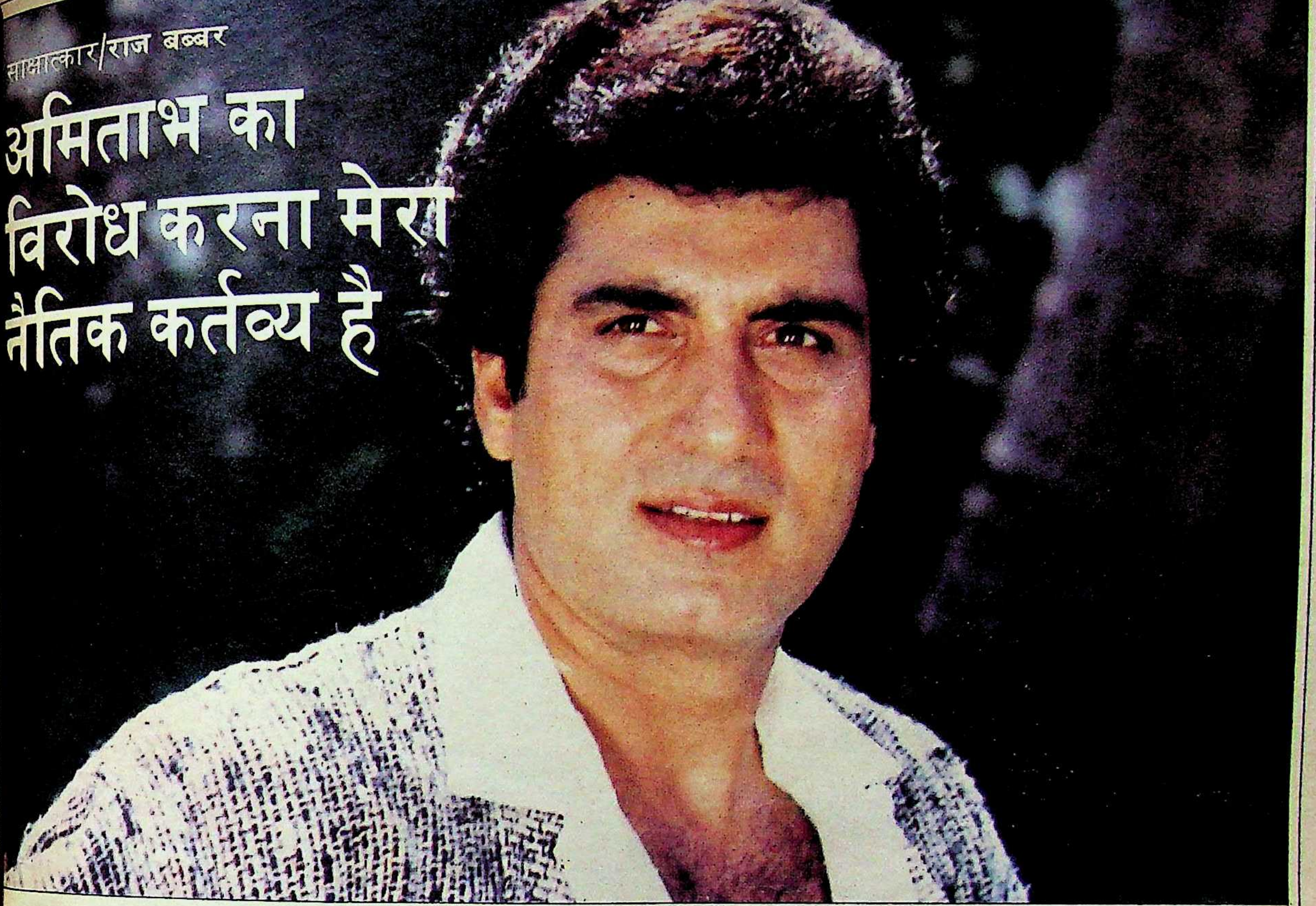

फ़ल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बाद र्वाधिक विवादास्पद अभिनेता राज बब्बर ाने जाते रहे हैं। अपनी पहली ही फिल्म इंसाफ का तराज़ू' से स्टार बन जाने वाले राज बब्बर का आगे का फिल्मी कैरियर बहुत सुनहरा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बहुतेरी फिल्में बिना सोचे-समझे ले लीं। शुरुआत की फिल्मों में लगा कि वह आम आदमी की भूमिका बड़े प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं। उनके चेहरे पर स्वाभाविक बेचारगी, संघर्ष से जूझने की पीड़ा और आत्मसम्मान का मिला-जुला जो भाव था, वह उनके अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान कर सकता था, लेकिन तब न तो उन्हें ऐसी पटकथा और न ही निर्देशक मिला जो उनकी इस खूबी को उभार सकता था। यहां तक कि उनकी आवाज में जो उतार-चढ़ाव था, उसका सहज और सही उपयोग भी नहीं किया जा सका, जबकि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज की इन्हीं विशिष्टताओं को 'अंडर टोन' और 'लाउड' बनाकर अपनी एक विशेष इमेज बना ली जो उनके स्टारडम को और भी निखारने में काफी सफल रही।

नैशनल स्कूल आफ ड्रामा के छात्र तथा दिल्ली रंगमंच पर बेहतरीन नाटकों में अपने अभिनय का सिक्का जमाने के बाद जब वह बंबई आये, तो बड़े-बड़े सितारों के साथ काम करते हुए भी वह 'कांशस' नहीं हुए। बल्कि सेकंड लीड में जहां कहीं भी वह आये, नायक-नायिका पर भारी साबित हुए। तब ऐसा लगा जैसे वह दूसरी पंक्ति के श्रेष्ठतम कलाकार हों। लेकिन ऐसी भूमिकाओं के लिए जरूरत होती है सशक्त पटकथा, संवाद एवं कुशल निर्देशन की। इसीलिए जब राज बब्बर को बीआर चोपड़ा के साथ, 'इंसाफ का तराज़ू' के बाद 'निकाह' में काम करने का मौका मिला, तो वह पुनः प्रखर हो उठे। एक दशक बाद श्री चोपड़ा की ही 'अवाम' में वह राजेश खन्ना पर (विमल कुमार की 'अगर तुम न होते' की तरह) हर क्षण हावी रहे।

१९८६ में सिनेमा बंद के दौरान जब वह आंदोलन के सूत्रधार के रूप में सामने आये, तो संगठन क्षमता और भाषणबाज़ी में हर जगह दूसरे सितारों से आगे रहे। उनकी इस विशिष्टता को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उनके सामने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सिद्धांत से लोहियावादी एवं समाजवादी मूल्यों में आस्था रखने के कारण इस आमंत्रण को उन्होंने न केवल नकार दिया, बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस से निकल आने के बाद उनके साथ जुड़ गये। इसके बाद वह उनके साथ-साथ हर जगह गये, विरोध भी सहा और प्रायोजित प्रदर्शनों का भी सामना किया, लेकिन कहीं भी पीछे नहीं हटे।

इसी के साथ शुरुआत हुई उनके अमिताभ बच्चन के साथ सीधे टकराव की। यों तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग थे, जो अमिताभ बच्चन के आलोचक थे, विरोधी थे, लेकिन खुलकर बोलने का साहस नहीं कर पाते थे। यह साहस दिखलाया राज बब्बर ने। वह अमिताभ को बतौर अभिनेता अति सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनकी अभिनय-क्षमता की कद्र करते हैं, लेकिन जैसे ही अमिताभ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उनके सामने आता है, वह बिदक उठते हैं।

राज बब्बर एक तरफ विद्रोही हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धांतवादी। एनएसडी में उन्होंने निदेशक अलकाजी के विरुद्ध आंदोलन की

पंखों पे चली आएं...ताज़ी ठंडी हवाएं!

ASP-OGI-304 E/88 HIN

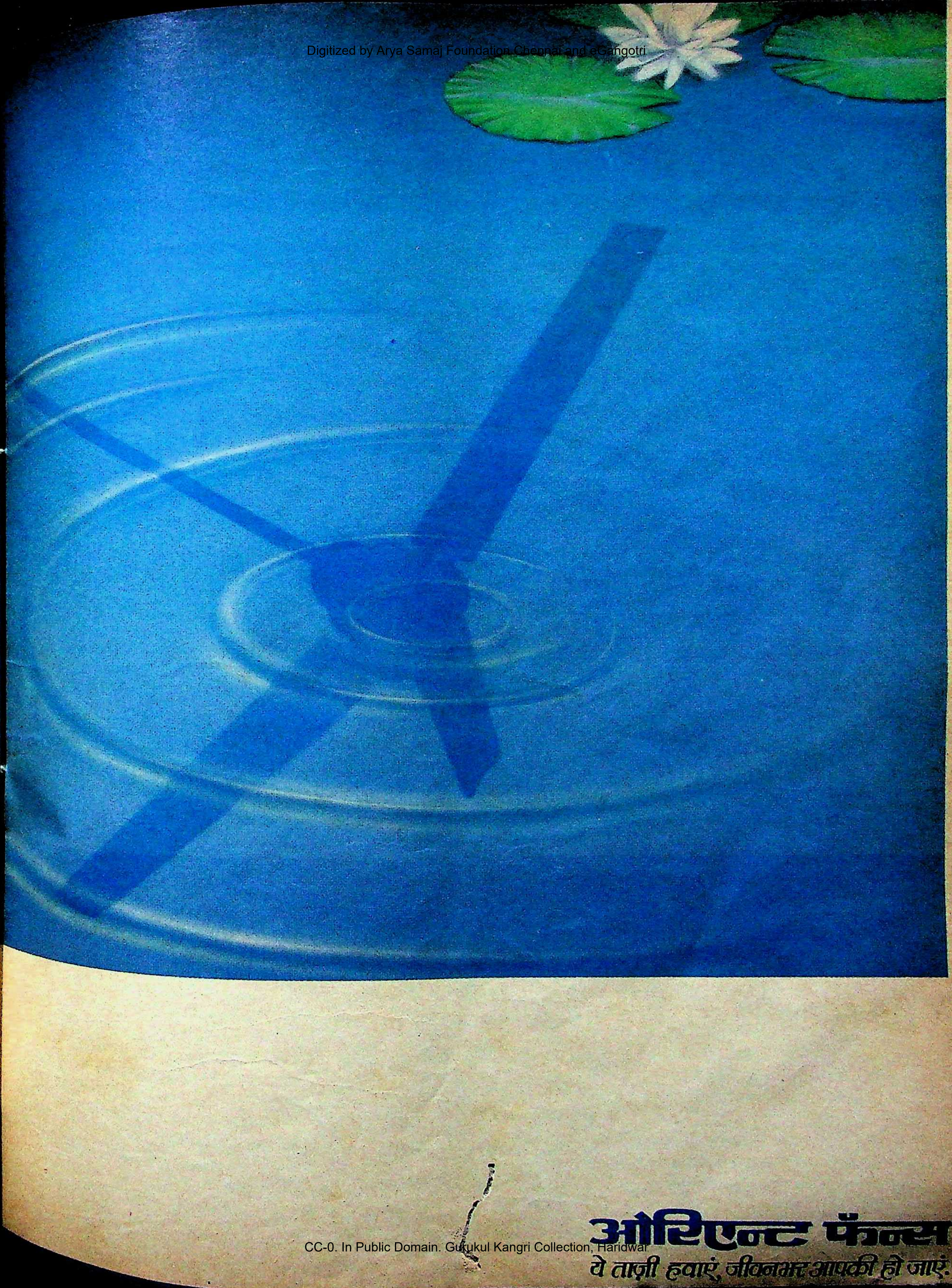
ओरिएन्ट फॅन्स
ये ताज़ी हवाएं, जीवनभर आपकी हो जाएं

अगुवाई की। फिल्म उद्योग में हड़ताल की नौबत आयी, तो वहां भी आगे आ खड़े हुए और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ राजीव गांधी तथा अमिताभ बच्चन के विरोध का मुद्दा उठ खड़ा हुआ, तो वहां भी वह सामने आ खड़े हुए। इसीलिए लोग बाग उन्हें दुस्साहसी और दृढ़-प्रतिज्ञ भी मानते हैं—इसका उदाहरण स्मिता पाटील के मामले में सबने भलीभांति देखा है, सारे अंतर्विरोधों के बावजूद उन्होंने स्मिता से अपने रिश्ते को खुलेआम कबूल कर लिया था। उन्हें धर्म में श्रद्धा है। उनके घर और कार्यालय में मंदिर है, इसीलिए वह चंद्रास्वामी के भी संपर्क में रहे और साईबाबा के नैकट्य में भी। जब सारी गाशिप पत्रिकाएं उनके और रेखा के अफेयर तथा तथाकथित विवाह की खबरों से भरी रहती थीं, वह हमेशा खामोश रह कर अफवाहों को हवा देते रहे। जाने-माने पत्रकार व पत्रिकाएं उनसे खुली बात करने के लिए उनके पीछे भागतीं और उन्हें घेरती रहीं, लेकिन वह बड़ी सफाई से हर किसी को गच्चा देकर खिसक जाते रहे। अंततः 'माया' से उन्होंने काफी लंबी बातचीत, बहुत सारे उन मुद्दों पर खुलकर की जिनसे वह हमेशा कतराते रहे थे। और बातचीत के बाद उन्होंने कहा—'चलो, एक बेहतर बात यह हुई कि लोगों को अब आगे साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घूम-फिर कर इन्हीं सवालों को दुहरायेंगे, तब मेरे लिए आसान होगा कि 'माया' में छपे साक्षात्कार की जीरोक्स प्रतियां उन्हें थमा दूंगा—यही सब कुछ है। अब बोलने के लिए बाकी क्या रहा!'

प्रस्तुत हैं, राज बब्बर से लंबी बेबाक बातचीत के अंश :

माया : *सक्रिय राजनीति में भाग लेने का मतलब, खासकर 'स्टार' श्रेणी के अभिनेताओं के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होना है। अपने हितों के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। फिर आपने विरोध का रास्ता क्यों चुना?*

राज बब्बर : पूरे देश की जनता को मद्देनजर रखते हुए जब किसी अहम मसले पर सोचा जाता है, तो व्यक्तिगत हितों की बात सोचना खुदगर्जी है। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना और आम आदमी के हक के लिए बेखौफ लड़ना, यह सिद्धांत मैंने तभी चुन लिया था, जब अपने छात्र जीवन में मैंने पालिटिक्स में कदम रखा था।

माया : *तब किस राजनीतिक विचारधारा से आप प्रभावित हुए थे?*

राज बब्बर : उस समय दो विचारधाराएं मुझ जैसे नवयुवकों को आकर्षित कर रही थीं। एक कम्युनिज्म, दूसरी समाजवादी। मुझे समाजवादी विचारधारा बहुत ही उचित और उपयुक्त लगी। डा० राममनोहर लोहिया के प्रखर विचारों और व्यक्तित्व में मुझे नयी रोशनी दिखायी दी। समाजवाद की जो जग उन्होंने छेड़ी थी, वह देश के लिए बहुत ज थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि लोहियाजी विचारों की अलख जगाने वाले कुछ नेता ही बाद में कुरसी के लालच में सुविधाओं के आत्मसमर्पण करके सत्ता के पिट्ठू बन गये। आज वे ही लोग देश सेवा के बजाय शासन करने की बात ज्यादा सोचने लगे हैं।

माया : *आपका मतलब है, मौजूदा सरकार है जिसके आगे बने रहने के आसार नहीं हैं,*

राज बब्बर : सरकार...यानी जिसे सत्तारूढ़ चला रही है...पार्टी कहां, यह तो एक 'डायनेस्टी' है, किसी एक वंश की मिल्कीयत दादागिरी से चल रही है।

माया : *देश के जैसे मौजूदा हालात हैं, उनमें क्या आप चाहते हैं कि फिर एक बार १९७७ के इतिहास की पुनरावृत्ति हो?*

राज बब्बर : दरअसल एक ही पार्टी को बार-बार शासन का मौका देकर जनता को अहसास हो गया है कि उसे भ्रष्टाचार के सिवा न तो कुछ मिला है और न आगे मिलने वाला है। जनता अब जाग चुकी है। पिंछले कुछ चुनावों और उपचुनावों ने साबित कर दिया है कि जनता डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समझती ही नहीं, उस पर उसे अमल करना भी आ गया है। मुझे इस बात पर यकीन है कि अब भारत की जनता समझ चुकी है कि किसी 'डायनेस्टी' को जीवित रखने के बजाय उसे जड़सहित उखाड़ने का समय आ गया है।

माया : *पंजाब समस्या की उम्र देखते-देखते लं होती जा रही है। उससे निजात पाने के लिए जो प्रयास किये गये, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं?*

राज बब्बर : पंजाब की समस्या को समस्या बनाये रखने में सरकार ने जितनी रुचि ली, उतनी इसे सुलझाने में नहीं। एक ऐसी 'कम्युनिटी' जिसने आजादी की लड़ाई से लेक हर आम और ख़ास मामलों में देश के साथ क से-कंधा मिलाया, आज अपने आपको 'सेकेंड सिटिजन' समझने लगी है। इस भावना को रोकने का काम क्यों नहीं हुआ, जबकि खुद 'कम्युनिटी' ऐसा चाहती थी और आज भी चाहती है।

माया : *तो आप क्या हल तजवीज करेंगे?*

राज बब्बर : उस 'कम्युनिटी' में, जो यह अहसास करने लगी है कि वह राष्ट्रीय धारा कट गयी है, उसमें ऐसा 'कांफिडेंस' पैदा करवाना होगा कि वह अपने आपको मुख्य ध से जुड़ी हुई समझे। उनके भीतर से वह डर निकालना होगा जिसके तहत वह अपने आप असुरक्षित समझने लगी है।

माया : *सरकार अब पंजाब में 'इमरजेंसी' ल चाहती है... ?*

राज बब्बर : आज तक ऐसा क्या नहीं किया सरकार ने, जो इमरजेंसी से कम था? पुलि

छाया : तैयब बादशाह

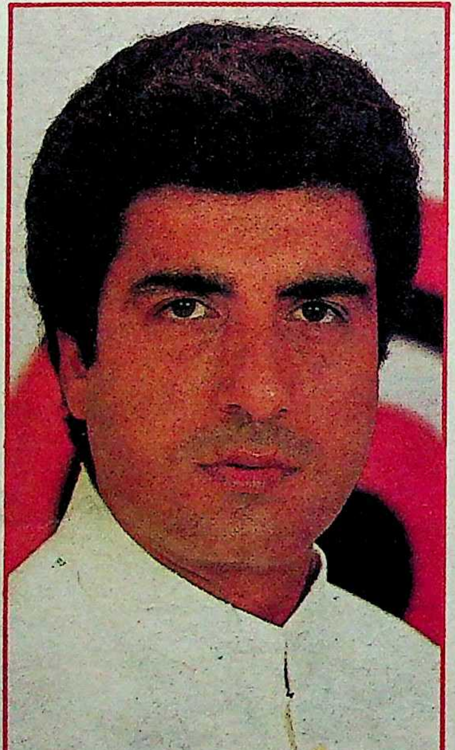

विश्वनाथ प्रताप सिंह एक शख्स नहीं, सचाई और ईमानदारी की एक परपंरा हैं। खास कर ऐसे समय में, जब राजनीति भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गयी है और ऐसे लोग नेतागिरी करने लगे हैं, जिनके हाथ काले हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लीडर की मुल्क को बहुत जरूरत है।

ना ने जब-जहां चाहा गोली चलायी। जब से चाहा गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ तो र लिया, अब और क्या चाहते हैं?

या: ***हाल ही शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने खों के बहिष्कार की बात कही है...क्या यह चित है?***

ज बब्बर: किसी एक शख्स के जो किसी खास म्युनिटी का नेता हो, ऐसा कहने से समस्या लझ नहीं, बल्कि और भी उलझ सकती है। ससे वे लोग जो अपने आपको मुल्क के साथ ड़ा समझते थे, कटा हुआ समझने लगेंगे। असुरक्षा की भावना आदमी से कुछ भी करवा सकती है। उसके अंदर के इंसान को गद्दार भी बना सकती है। जरूरत तो यह है कि ऐसी भेदभाव भरी बातों के बजाय, उन्हें यह अहसास करवाया जाये कि वे मुल्क और समाज के आवश्यक अंग हैं। उनकी कुरबानियां मुल्क को आगे बढ़ाने में दी गयीं। उनकी (सिखों की) जद्दोजहद कभी भुलायी नहीं जा सकती।

माया: ***जिन आदर्शों की राजनीति में आपको खोज है, क्या उसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व सबसे उपयुक्त है?***

राज बब्बर: बेशक। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक शख्स नहीं, सचाई और ईमानदारी की एक परंपरा है। खास कर ऐसे समय में जब राजनीति भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गयी है और ऐसे लोग नेतागिरी करने लगे हैं जिनके हाथ काले हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लीडर की मुल्क को बहुत जरूरत है। भ्रष्टाचार को खतम करने और सत्ता से टक्कर लेने की ऐसी हिम्मत भला है किसी के पास?

माया: ***विश्वनाथ प्रताप सिंह को इलाहाबाद के उपचुनाव में खड़ा होना चाहिए या नहीं?***

राज बब्बर: बिलकुल। विश्वनाथ प्रताप सिंह का इलाहाबाद अपना घर है और मैं समझता हूं कि उन्होंने इलाहाबाद की परंपरा को जिंदा रखा है।

माया: ***अगर वीपी सिंह चुनाव में खड़े होंगे, तो आप उनके चुनाव प्रचार के लिए वहां जायेंगे?***

राज बब्बर: अगर मुझे इस काबिल समझा गया, तो जरूर जाऊंगा। मगर एक फिल्म स्टार की हैसियत से नहीं, आम 'वर्कर' की हैसियत से।

माया: ***इसे मजाक में लें या सच में, वीपी सिंह को क्या जरूरत है अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होने की। जब अभिनेताओं की लोकप्रियता को वोट का मुद्दा बनाना है, तो क्यों न 'रामायण' टीवी सीरियल के 'राम' यानी अरुण गोविल को उनके मुकाबले खड़ा कर दिया जाये?***

राज बब्बर: (हंसी) यह तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। यह आइडिया आप राजीव गांधी को दे दीजिये, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा।

माया: ***अगर अमिताभ बच्चन चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके फिल्म उद्योग के दोस्त भी चुनाव प्रचार के लिए इलाहाबाद जायेंगे। तब क्या यह नहीं होगा कि दो फिल्मी गुट बन जायें और टकराव पैदा हो जाये?***

राज बब्बर: एक अभिनेता की हैसियत से अमिताभ बच्चन के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आता है, तो मैं उसे बजाय अभिनेता के सिर्फ एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में क्यों न देखूं, जिसकी विचार धारा मुझसे मेल नहीं खाती। उसका विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। रहा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से टकराव का सवाल, सो ऐसा होना गैरजरूरी इसलिए है, क्योंकि राजनीति हमें रोटी नहीं देती। रोटी तो हमें इंडस्ट्री ही देती है। अमिताभ के मित्रों में मेरे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो क्या राजनीतिक मतभेद के कारण मैं उनकी फिल्में छोड़ दूं, या वे मुझे फिल्मों में लेना छोड़ देंगे, अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर टकराव किस बात का?

माया: ***आपने बड़ी तादाद में फिल्में साइन कीं, मगर बहुत कम चलीं। आपके राजनीति में आने का कारण भी यही बताया जा रहा है?***

राज बब्बर: (हंसी) फिल्में नहीं चलतीं, तो हीरो भी नहीं चलता, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का मानना है। मेरी फिल्में नहीं चलीं, तो मुझे भी नहीं चलना चाहिए था। मगर पिछले कई सालों से तीन-तीन शिफ्टों में काम कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि इस वक्त सैंतालीस फिल्मों में काम कर रहा हूं। राजनीति से पहले मैं अपने पेशे को मानता हूं, जो मेरे लिए हर की पैड़ी की गंगा की तरह पवित्र है। मेरा धर्म है मेरा पेशा, यानी कि अभिनय। इसमें जो भी तरक्की मैं कर सकता हूं, उसके लिए पूरी जद्दोजहद करूंगा। इससे जो भी उपलब्धियां मुझे प्राप्त होंगी, उनका इस्तेमाल मैं समाज के उन लोगों के लिए करूंगा, जिनकी वजह से मेरा 'प्रोफेशन' जिंदा है। राजनीति में मेरे भाग लेने के पीछे न तो कोई स्वार्थ है न कोई महत्वाकांक्षा...।

माया: ***फिल्म उद्योग की भलाई के बारे में भी आपने कुछ सोचा है? ब्लैकमनी के बारे में आपकी क्या राय है?***

राज बब्बर: फिल्म उद्योग की भलाई तभी हो सकती है जब चार सौ करोड़ रुपए सालाना सरकार को देने वाले इस उद्योग को सरकार द्वारा मान्यता मिले। अभी तो हालत यह है कि टेप जैसी मामूली चीज भी विदेशों से आती है, और ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। जिस दिन इस इंडस्ट्री को बैंक फायनेंस करने लगेंगे और अपने देश में मैटिरियल बनने लगेगा, तो वह भ्रष्टाचार भी खतम हो जायेगा जो निर्माताओं को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर करता है। ऊपर का भ्रष्टाचार खतम होगा, तो इंडस्ट्री के भीतर पनपने वाले भ्रष्टाचार का भी अंत हो जायेगा। कालेधन की 'प्राबलम' भी आपसे-आप खतम हो जायेगी।

—हरीश तिवारी

> एक अभिनेता की हैसियत से अमिताभ बच्चन के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आता है, तो मैं उसे बजाय अभिनेता के सिर्फ एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में क्यों न देखूं, जिसकी विचारधारा मुझसे मेल नहीं खाती। उसका विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य है।

भगवानों से सावधान !

स्वामी प्रज्ञानंद

आज धर्म तथा धर्म की अवधारणा के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं, उतनी पूर्वकाल में कभी नहीं रहीं। यह सर्वविदित तथ्य है कि भ्रांति अशांति की जननी है तथा अशांति क्रांति का आह्वान है, आमंत्रण है। संसार के अनेक स्थलों पर धर्म ने एक सुव्यवस्थित व्यापार तथा योग ने एक उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया है। फलस्वरूप धर्म की स्पष्ट अवधारणा के अभाव में धर्माचार्यों, तथाकथित गुरुओं, संतों, महंतो, अवतारों एवं भगवानों से धर्म को सर्वाधिक खतरा पैदा हो गया है। यह सार्वभौम सत्य है कि मंत्री को अपने अंगरक्षक से, गुरु को शिष्य से, भगवान को भक्त से, नेता को अनुयायी से, मंदिर को पुजारी से जितना भय अथवा खतरा रहता है, उतना किसी अन्य से नहीं।

जनसंख्या के साथ भक्तों, महंतों, गुरुओं, आचार्यों, अवतारों एवं भगवानों की संख्या में भी अभिवृद्धि हुई है। १९९२ की जनगणना के अनुसार लगभग सात लाख ग्रामोंवाले हमारे देश में साधुओं की संख्या ५६ लाख के लगभग थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च के नाम पर प्रायः प्रत्येक ग्राम में कम-से-कम एक देवालय तो पाया ही जाता है। इसी अनुपात में अवतारों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ८० भगवानों की सूची गत दिनों प्रकाशित हुई थी, यह बात और है कि उसमें से पचास प्रतिशत 'भगवान' हेराफेरी एवं तस्करी जैसे कार्यों में संलग्न पाये गये थे। 'गुरु' शब्द के अर्थ का जितना संकुचन तथा अवमूल्यन हुआ है, उतना शायद ही किसी अन्य शब्द का हुआ हो। गुरु का अर्थ आज सबसे चालाक एवं जालसाज व्यक्ति से लिया जाता है। बातचीत में 'क्यों गुरु क्या हाल है' सामान्य उक्ति बन गयी है। 'गुरु हो जा शुरू' नामक फिल्म ही बन गयी है। शिष्यों को अंधी भेड़ें समझकर अच्छी तरह मूंड़नेवाले तथा श्रद्धा का दोहन कर अनाप-शनाप सम्पत्ति बटोरने वाले गुरुओं, आचार्यों की भरमार आकस्मिक नहीं है।

ईमानदार कौन ? : वस्तुतः अपने आपको भगवान कहने वाला धूर्त है तथा जो धूर्त को भगवान मानता है, वह मूर्ख है। पाश्चात्य देशों में कुत्ते पालनेवाले अपने घर के बाहर यह सूचनापट लगाते हैं कि 'कुत्तों से सावधान' (बी वेयर आफ डाग्स)। हमने अफ्रीका, यूरोप एवं अमरीका के भगवान-प्रेमियों के घरों के समक्ष एक और सूचना पट लगाने की पहल की है, 'भगवानों से सावधान' अर्थात (बी वेयर आफ गाड्स), क्योंकि 'डाग्स' (कुत्ते) ईमानदार हैं, केवल अपरिचितों को ही काटते हैं, जबकि तथाकथित 'गाड्स' अपने परिचितों-शिष्यों की जेबें काटते हैं। 'गाड्स' का उलटा 'डाग्स' होता है। दोनों से सावधान रहने की चेतावनी दी गयी है। वैसे, तात्विक दृष्टि से भगवान से डरना बुरा नहीं है। यहां तो, भगवानों से डरने की बात पर जोर दिया गया है, क्योंकि भगवान तो एक है, अनेक नहीं।

धर्म का अर्थ गुण एवं कर्म है। किसी व्यक्ति एवं वस्तु की प्रकृति एवं स्वभाव का नाम धर्म है। चंदन की प्रकृति अथवा स्वभाव सुगंध है, इसलिए चन्दन का धर्म भी सुगंध है। नमक का धर्म खारापन, शक्कर का मिठास तथा नीम का कडवाहट है। 'जो गुण व्यक्ति एवं वस्तु में निहित है, उसमें घुलामिला है, मिश्रित है, अपरिवर्तन-शील है, सार्वभौम है, उसे ही सनातन कहते हैं।' जो मानव के तन, मन एवं जीवन में समाहित है वही मानव का सनातन धर्म अथवा मानव धर्म है।

आज पशुओ ने एवं वस्तुओं ने अपना गुण, स्वभाव अर्थात धर्म नहीं छोड़ा, किंतु मनुष्य ने अपना स्वभाव छोड़ दिया है। इसलिए दुखी है। वृक्षों ने फल देना, नदियों ने जल देना तथा गायों ने दूध देना नहीं छोड़ा, इसलिए वे अनुकरणीय हैं। इसी कारण पशु-पक्षी कम बीमार पड़ते हैं।

समग्र ब्रह्मांड का सृजक, पालक एवं संहारक एक ही परमात्मा है। वेदों में उसे 'एक सद् विप्रा-बहुधा वदन्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है। उस स्वयंभू एक परमब्रह्म द्वारा रचित अपौरुषेय धर्म दो नहीं हो सकते, इसलिए समस्त मानव जाति के लिए एक ही मानव धर्म हो सकता है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। पंथ अनेक हैं, क्योंकि वे अनेक पुरुषों, महापुरुषों, तीर्थंकरों, पैगम्बरों द्वारा प्रवर्तित हैं। इसलिए पंथ पौरुषेय कहलाते हैं। पुरुष की सीमा है इसलिए उसके द्वारा प्रवर्तित पंथ संप्रदाय की सीमा है, जबकि अपौरुषेय प्रभु असीम व अनंत हैं। इसलिए धर्म अंतहीन एवं असीम है। मात्र ही ईश्वर निर्मित अर्थात प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा सबके लिए है, जबकि मानव निर्मित एवं पुरुष प्रदत्त संप्रदाय एवं पंथ एक समाज एवं एक वर्ग विशेष के लिए हैं। ईश्वरीय सम्पदा पर सबका अधिकार होता है। भगवान के सभी पुत्र समान हैं, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। धर्म मानव को मानव से जोड़ने के लिए

तोड़ने के लिए नहीं, जबकि पंथ एवं संप्रदाय मानव को मानव से तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, भेदभाव की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। धर्म प्रेम पैदा करता है और पंथ घृणा पैदा कर रहे हैं।

आजकल जगह-जगह धर्म के नाम पर झगड़े सुनाई देते हैं। वास्तव में झगडा धर्म का नहीं पंथों का है। धर्म निःस्वार्थ है और पंथ स्वार्थ है। स्वार्थ ही इन्सान इन्सान को लड़ाता है, धर्म मुफ्त में बदनाम होता है। धर्म अखण्ड मानवता का प्रतीक है, जबकि पंथ मानव समाज को खण्ड-खण्ड कर रहे हैं। 'जिओ और जीने दो' की आचार-संहिता में ही सच्चा धर्म सन्निहित है, अतएव आर्ष वांग्मय में 'आचार प्रथमो धर्मः', आचरण को ही प्रथम धर्म कहा गया है।

जन्म से सभी मनुष्य सनातनी होते हैं, धार्मिक होते हैं। जन्म के बाद पंथ विशेष के पंथी और ग्रंथ विशेष के ग्रंथी बनते हैं। नवजात शिशु को देखकर उसे मानव ही कहा जा सकता है। जन्म से न कोई मुसलमान होता है, न हिंदू होता है, न सिख होता है और न ही ईसाई होता है।

जन्म के समय बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, मुहम्मद, गुरुनानक सभी इन्सान थे अर्थात् सनातनी थे। बुद्ध के बाद दुनिया को त्रिपिटक ग्रन्थ तथा बुद्ध पंथ मिला, तीर्थंकरों एवं महावीर के बाद धम्मपद तथा जैन पंथ मिला। जीसस क्राइस्ट के बाद बाइबिल तथा ईसाइयत मिली, मुहम्मद साहब के बाद कुरान तथा इस्लाम मिला, गुरुनानक देव के बाद गुरुग्रंथ साहब तथा सिख पंथ मिला। इसलिए बुद्धमत से यदि बुद्ध को, जैन से २४ तीर्थंकरों को, ईसाइयत से क्राइस्ट को, पारसी से जरदुश्त को, सिख पंथ से दस गुरुओं को और यहूदी से मोजेज को अलग कर दें, तो उक्त पंथों में कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि सनातन धर्म से यदि श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा २४ अवतारों को भी निकाल दें, तब भी सनातन धर्म शेष रहेगा। श्रीराम एवं श्रीकृष्ण सनातन धर्म के संरक्षक तो थे, किन्तु प्रवर्तक नहीं। साधु-सन्तों एवं सज्जनों से धर्म जीवित रहता है और दुष्टों-दानवों से धर्म को खतरा होता है, इसलिए अवतार साधु-संतों की रक्षा एवं दुर्जनों के विनाश के लिये होते हैं।

वसुधैव कुटुम्बकम :यदि सनातन धर्म को हम 'पावरहाउस' कहें, तो पंथों को ट्रान्सफार्मर कह सकते हैं। देशकाल, वातावरण के अनुरूप महापुरुषों ने पंथों को प्रारम्भ किया और मूल प्रकाश की धारा एक पावर हाउस रूपी सनातन धर्म से मिलती रही। सार्वभौम सनातन धर्म में श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अहिंसा, करुणा, दया, सत्य, प्रेम, पवित्रता, सेवा, सद्भाव, भाईचारा, गुरुभक्ति का समावेश है। सनातन धर्म से बुद्ध ने करुणा ली, महावीर ने अहिंसा ली, क्राइस्ट ने सेवा भावना ली, मुहम्मद साहब ने भाईचारा लिया, मोजेज ने सत्प्रेम लिया, जरदुश्त ने पवित्रता ली, दयानन्द ने विवेक लिया, गुरुनानक ने गुरुभक्ति ली। आज 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सनातन भाव की संस्थापनार्थ इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। वस्तुतः 'साम्प्रदायिक-सद्भाव, लोक-कल्याण, विश्व-शांति, विश्व-बन्धुत्व, एवं मानव-धर्म के लिए आज हमें बुद्ध एवं करुणा चाहिए, बुद्धवाद नहीं, हमें महावीर एवं अहिंसा चाहिए, जैनवाद नहीं, हमें क्राइस्ट व सेवा भावना चाहिये, ईसाईवाद नहीं, हमें मुहम्मद साहब और भाईचारा चाहिये, इस्लामवाद नहीं, हमें जरदुश्त व पवित्रता चाहिये, पारसी पंथ नहीं, हमें मोजेज और यहूदी का सत्प्रेम चाहिये, यहूदी मत नहीं, गुरुनानक देव तथा गुरुभक्ति चाहिये, सिख पंथ नहीं, क्योंकि वादों, मतों, पंथों एवं सम्प्रदायों के नाम पर मानवता एवं मानव धर्म अर्थात् सनातन धर्म खण्ड-खण्ड होकर बिखरता-टूटता जा रहा है। विश्व को आज मानवता को विभाजित करनेवाले नहीं, बल्कि समायोजित करनेवाले, जोड़नेवाले सच्चे पीर चाहिए, जो पर-दुख कातरता एवं संवेदना को अपना धर्म मानते हों। ऐसे आस्तिक चाहिए जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हों।

सनातन धर्म जीभ के समान है तथा दांत पंथों के समान हैं। जीभ एक ही होती है और दांत बत्तीस। जीभ मानव के जन्म के साथ आती है तथा आजीवन बनी रहती है। जबकि दांत जन्म के बाद आते हैं तथा मृत्यु के पूर्व ही गिर जाते हैं। दांत जब निकलते हैं, तब बच्चों को तकलीफ देते हैं। कठोरता के कारण दूध के दांत बाल्यकाल में ही गिर जाते हैं तथा फिर निकलते हैं एवं वृद्धावस्था में गिरते समय पुनः कष्ट देते हैं, क्योंकि दांत कठोर हैं, कट्टर हैं पंथों की तरह, जबकि जीभ नरम, लचीली एवं सहिष्णु है, धर्म के समान। धर्म कट्टरता का नहीं कोमलता का नाम है। धर्म राष्ट्रीय मार्ग के समान हैं और पंथ तथा सम्प्रदाय अनेक पगडंडियों के समान हैं जो समय-समय पर राष्ट्रीय मार्ग से बिछुड़ती एवं जुड़ती रहती हैं। ■

जन्म के समय बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, मुहम्मद, गुरुनानक सभी इंसान थे अर्थात् सनातनी थे। बुद्ध के बाद दुनिया को त्रिपिटक ग्रंथ तथा बुद्ध पंथ मिला, तीर्थंकरों एवं महावीर के बाद धम्मपद तथा जैन पंथ मिला। जीसस क्राइस्ट के बाद बाइबिल तथा ईसाइयत मिली, मुहम्मद साहब के बाद कुरान तथा इस्लाम मिला, गुरुनानक देव के बाद गुरुग्रंथ साहब तथा सिख पंथ मिला। इसलिए बुद्धमत से यदि बुद्ध को, जैन से २४ तीर्थंकरों को, ईसाइयत से क्राइस्ट को, पारसी से जरदुश्त को, सिख पंथ से दस गुरुओं को और यहूदी से मोजेज को अलग कर दें, तो उक्त पंथों में कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि सनातन धर्म से यदि श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा २४ अवतारों को भी निकाल दें, तब भी सनातन धर्म शेष रहेगा।

जब पाकिस्तान में कहर टूटा

हीरोशिमा जैसा दृश्य: दूर-दूर तक पड़े शव

१० अप्रैल को पौने दस बजे अचानक एक जबर्दस्त धमाका हुआ और एकाएक राजधानी इस्लामाबाद व रावलपिंडी में मिसाइलों-राकेटों और बमों की बरसात होने लगी। बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें घबराकर घरों, दफ्तरों और स्कूल-कालेजों से निकल आये। हर तरफ अफरातफरी और भगदड़ मची हुई थी। चारों ओर खून और आग के भयंकर साये फैलने लगे थे। गिरते हुए राकेटों-बमों ने तबाही मचा दी थी। एक घंटे से भी कम समय में हजारों लोग मृत और जख्मी हो गये। ५००० से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गयीं। इंसानी जिस्मों के टुकड़े और गोश्त के लोथड़े बिजली के तारों में उलझ रहे थे। दोनों शहरों को गहरे धुएं और आग की लपटों ने अपने दामन में छिपा लिया। जब राकेटों और बमों की वर्षा थमी, तब कहीं पता चला कि असल बात क्या है?

सरकार ने ऐलान किया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच ओजड़ी सैनिक कैंप के हथियार डिपो में एक ट्रक पर गोला-बारूद लादते समय आग लग गयी, जिससे भंडार में रखे हुए राकेट, मिसाइल और बम फट पड़े। सरकार कहती है कि इसमें १०० मरें और ११०० जख्मी हुए, लेकिन जिन्होंने यह तबाही अपनी आंखों से देखी है, उनका अनुमान है कि मरने वालों की संख्या ३००० से कम नहीं होगी। उनका कहना है कि धमाके के समय केवल ओजड़ी कैंप में ही लगभग १००० लोग मौजूद थे। सैनिक डिपो के साथ ही सर्वे आफ पाकिस्तान का कार्यालय था, जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। पास में दुकानें व फ्लैट हैं। खुद सैनिक डिपो के कंपाउंड में ४० सैनिकों के घर थे। इन सब लोगों का क्या हश्र हुआ? हथियार डिपो से धमाके के वक्त निकलनेवाले राकेटों और बमों ने १० किमी क्षेत्र में हर चीज को तहसनहस करके रख दिया। फिर यह कैसे संभव है कि इतने खौफनाक धमाके में केवल १०० लोग मरे हों। शायद सरकार झूठ बोलकर जनता को बहलाना और अपना बचाव करना चाहती है।

आर्थिक क्षति का कम-से-कम अंदाजा ५० करोड़ रुपए बताया जाता है। लेकिन जो लोग इस हादसे में मर गये, उनकी कीमत का अंदाजा कौन लगायेगा? धमाके के फौरन बाद शहर में विभिन्न अफवाहें फैल गयीं। कुछ ने कहा भारत ने हमला कर दिया है और शहर पर भारतीय उपग्रह राकेट-बम बरसा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस्राइल ने कहुटा के एटमी प्लांट पर हमला कर दिया है। कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि सोवियत संघ ने मिसाइलों से हमला किया है, जबकि कुछ यह कहते सुने गये कि अफगान उग्रवादियों ने बमों-राकेटों से शहर पर चढ़ाई कर दी है।

तबाही का आलम: बहरहाल जब रेडियो-टेलीविजन पर ऐलान हुआ कि किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि ओजड़ी डिपो में धमाका हुआ है, तब लोगों की जान में जान आयी। लेकिन बहुत से लोग रेडियो-टीवी का यह ऐलान न सुन सके। क्योंकि नगर प्रशासन ने आग लगने के डर से बिजली काट दी थी। इसके अलावा हजारों लोग घरों से निकल कर सुरक्षित स्थलों की खोज में दौड़-भाग रहे थे। किंतु मौत हर जगह उनका पीछा कर रही थी।

राकेट और बम संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय सचिवालय पर भी गिरे। आई-९ सेक्टर में दो बड़ी फैक्ट्रियां पूर्णतया तबाह हो गयीं। इस्लामाबाद हवाई अड्डे के र पर ६ मिसाइलों के गिरने से बड़े-बड़े गड्ढे हो गये। वायुसेना के चकलाला हवाई अड्डे को भी नुकसान पहुंचा। वायुसेना के चार अफसर मरे और बाकी जख्मी हो गये।

फौजी डिपो के करीब टेलीफोन एक्सचेंज पर १५ राकेट गिरे, जिससे एक्सचेंज तबाह हो गया और इलाके के तमाम टेलीफोन कनेक्शन भंग हो गये। अनगिनत लाशें ऐसी मिली हैं कि जिनके सिर धड़ से गायब थे। किसी का बाजू उड़ गया था, तो किसी की टांग गायब थी। धमाके के बाद शहर के विभिन्न स्कूलों में छुट्टी कर दी गयी और शिक्षक भाग खड़े हुए। इसके कारण हजारों बच्चे घबराहट में न जाने कहां-कहां चले गये। इनमें से सैकड़ों बच्चे अभी तक अपने घर नहीं लौटे और उनके मां-बाप उनकी याद में रो-रो कर पागल हो चुके हैं।

मुसीबत की इन घड़ियों में जहां हजारों लोगों ने स्वयंसेवी तरीके से प्रभावित लोगों की मदद की, उनके घरों तक पहुंचाया, ब्लड बैंक में खून दिया, घरों में लगी हुई आग बुझाई, वहीं असामाजिक तत्वों ने अपना मुंह काला करने में भी शर्म नहीं की। डर के मारे घर छोड़कर जानेवाले लोगों के कीमती सामान चोरी कर लिये गये। गिरे घरों का मलवा हटाने और सहायता करने के बहाने चोरो ने लूटमार शुरू कर दी। अफरातफरी और भगदड़ के दौरान लगभग ४ हजार लोग लापता हो गये। इनमें से अधिकांश का आज तक पता नहीं लग पाया है।

शहर से राकेट-बम साफ करने में लगी १७० फौजी टीमों ने दो दिन के अंदर करीब ३० हजार बमों और राकेटों के खोल उठाये हैं। एक अनुमान के अनुसार सैनिक डिपो से लाख से ज्यादा राकेट, मिसाइल और बम धमाके के बाद चारों ओर फैल गये। फौजी अधिकारियों ने बताया कि इनमें से अधिकांश राकेट-बम फटे नहीं वरना बहुत अधिक नुकसान होता। उन्होंने बताया कि राकेटों-मिसाइलों पर 'वार हेड्स' नहीं लगे हुए थे। इमारतों को क्षति केवल राकेट और मिसाइलों की फ्लाइंग स्पीड से पहुंची है। अगर उनमें 'वार हेड्स' लगे हुए होते, तो इससे जो भयानक तबाही होती, वह अकल्पनीय थी।

लोगों ने बताया कि रावलपिंडी के धमाकों से हीरोशिमा पर एटम बम गिरने का दृश्य सामने आ गया था। ओजड़ी कैंप में ध दूसरे और तीसरे दिन भी जारी रहे। दूसरे

तीसरे दिन तीन-तीन मिसाइल उड़कर बाहर जा गिरे, लेकिन उनसे कोई हताहत नहीं हुआ। पहले दिन होनेवाले धमाकों के बाद दो रोज तक कैंप में आग लगती रही और धुआं उठता रहा। बताया जाता है कि धमाको से दो डिपो पूरी तरह तबाह हो गये, जबकि हथियारों का तीसरा डिपो सुरक्षित रहा। लोग अपने घरों से इसलिए भाग खड़े हुए थे कि किसी ने अफवाह फैला दी कि तीसरा डिपो भी फटनेवाला है।

धमाके में हजारों लोगों के मरने और जख्मी होने की खबरें जब लंदन, न्यूयार्क, जेद्दा, दुबई और भारत पहुंचीं, तो वहां रहनेवाले उनके रिश्तेदार बेहद परेशान हुए और इन जगहों से आनेवाले टेलीफोनों का तांता बंध गया। लेकिन सेटलाइट टाउन टेलीफोन एक्सचेंज के तबाह हो जाने से हजारों टेलीफोन कनेक्शन कट चुके थे, जिसके कारण लोगों को अपने रिश्तेदारों से संपर्क का मौका नहीं मिल पाया।

रावलपिंडी के समीपवर्ती शहर से अनगिनत लोग ट्रकों, बसों व प्राइवेट कारों के द्वारा अपने संबंधियों की खबर मालूम करने के लिए पहुंचे। इससे दोनों शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी और बेचैनी फैल जाने से अनेक सड़क दुर्घटनाएं हुईं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद खान अब्बासी-जो धमाके का हाल जानने के लिए अपने आफिस से निकले ही थे–कि कार को राकेट लगा, जिससे वह घटनास्थल पर ही मारे गये।

सरकार ने धमाके से पीड़ितों की मदद के लिए ५ करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि इतना जबर्दस्त नुकसान हुआ है कि इसके लिए ५० करोड़ रुपए भी नाकाफी हैं।

जिया कुवैत में: रावलपिंडी व इस्लामाबाद पर जब राकेट बम बरस रहे थे, उस समय राष्ट्रपति जिया कुवैत में होनेवाली मिनी इस्लामिक शिखर वार्ता में शरीक थे। सूचना मिलते ही वह अपना दौरा खतम करके पाकिस्तान वापस आ गये। पहले पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा, यह धमाका आकस्मिक हो सकता है। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि उसमें तोड़-फोड़ हुआ है, क्योंकि दुबई से आनेवाले चार अमरीकी विशेषज्ञों को ओजड़ी कैंप से ऐसे सुराग-सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल या टाइम डिवाइस के जरिये तीन धमाके किये गये।

हालांकि प्रधानमंत्री जुनेजो ने धमाके की जांच-पड़ताल के लिए कोर कमांडर ले० जनरल इमरान के नेतृत्व में एक जांच समिति कायम कर दी है, लेकिन विपक्षी नेताओं, भूतपूर्व जनरलों और एयर मार्शलों ने मांग की है कि इस दुर्घटना की जांच जन प्रतिनिधियों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से करायी जाये। इन लोगों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि ओजड़ी कैंप को शहर से बाहर क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया। ३ साल पहले संसद में विपक्षी सदस्य मुमताज अहमद ने मांग की थी कि इस कैंप से चारों ओर आबादी अधिक होने से इसे अन्यत्र स्थानांतरित कर देना चाहिए। सुरक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि कैंप को जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

विपक्षी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द-से-जल्द अफगान शरणार्थियों को उनके वतन भेजे और रूस और भारत से संबंध बेहतर बनाये। क्योंकि अगर इन दोनों देशों से संबंध अच्छे न बनाये गये, तो डर है कि देश में ऐसी और भयानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

रावलपिंडी के धमाके में तोड़-फोड़ की आशंका इसलिए भी की जा रही है, क्योंकि उसी दिन लाहौर की एक बारूद बनानेवाली फैक्ट्री में धमाका हुआ जिससे १६ लोग मरे व १० घायल हो गये। उसी दिन रात में कराची में सऊदी एयर लाइंस के दफ्तर में बम का धमाका हुआ। इससे उस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा और करोड़ों रुपए मूल्य के कंप्यूटर तबाह हो गये।

पाकिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष बिजेंजो ने कहा कि वह इस बात पर बड़े खुश थे कि अफगान समस्या के हल के लिए कई साल की कोशिशों के बाद जिनेवा में हस्ताक्षर होनेवाले हैं, लेकिन रावलपिंडी की दुर्घटना ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया है।

बताया जाता है ओजड़ी फौजी कैंप के पास एक विदेशी मिशनरी केंद्र का कार्यालय भी था, जो मलबे का ढेर बन गया। धमाके के दूसरे दिन दो विदेशी इस मलबे में अपना सामाना तलाश करते देखे गये। इलाके के लोगों ने इस बात पर गहरे अचंभे का इजहार किया कि इतने संवेदनशील इलाके में एक विदेशी मिशनरी को अपना कार्यालय कायम करने की किस तरह इजाजत दी गयी और इसके पीछे क्या उद्देश्य और रहस्य था?

रावलपिंडी के हाल के धमाकों से राष्ट्रपति जिया की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि यह विपत्ति अल्लाहताला की ओर से आयी है। लोग कहते हैं कि बेशक अल्लाह की तरफ से यह कहर बरपा हुआ, लेकिन यह शासकों का फर्ज था कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय और प्रबंध करते। यदि तबाही और बर्बादी को सरकार नहीं रोक सकती, तो उसको सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है।

इस्तीफे की मांग: एक अफवाह यह भी है कि रावलपिंडी में धमाके भारत ने कराये थे, जिससे कुछ दिनों पहले जबलपुर के सैनिक डिपो में होने वाले धमाकों का बदला लिया जा सके। विपक्षी नेताओं, संसद सदस्यों, अनेक पूर्व फौजी जनरलों और एयर मार्शलों ने मांग की है कि राष्ट्रपति जिया और प्रधानमंत्री मोहम्मद खां जुनेजो जनता की जान-माल की रक्षा में नाकाम रहे, इसलिए अपने पदों से इस्तीफा दे दें।

विपक्षी नेताओं और जन प्रतिनिधियों ने रावलपिंडी तथा इस्लामाबाद में होने वाली तबाही के संबंध में कुछ सवाल उठाये हैं। उनका कहना है कि आबादी के बीच सैनिक साजोसामान के डिपो को कायम रखने की क्या आवश्यकता थी? और यदि उस डिपो को वहां से हटाया नहीं जा सकता था, तो उसकी सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध क्यों नहीं किये गये? वह यह भी कहते हैं कि ओजड़ी कैंप में इतने अधिक हथियार रखने का असली कारण क्या था? यह बात कतई नहीं मानी जा सकती कि इतने सारे हथियार इस्लामाबाद में रहनेवाले वीआईपी लोगों की सुरक्षा के निमित्त थे। आम राय यह है कि महाशक्तियों के हितों-स्वार्थों की लड़ाई में पाकिस्तान की गरीब जनता मारी जा रही है। पश्तो भाषा की एक कहावत है—'भैंसों की लड़ाई में मेढक कुचले जाते हैं।' यही हाल पाकिस्तानी जनता का भी है।

यह बात काफी हद तक सही है कि जिनेवा में होनेवाले अफगान समस्या के समाधान के समझौते पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जिया ने अपनी गद्दी को काफी हद तक मजबूत कर दिया है, क्योंकि जनता की ख्वाहिश यही है कि रूसी सेनाएं अफगानिस्तान से निकल जायें और पाकिस्तान में ठहरे हुए ३० लाख अफगान शरणार्थी अपने देश वापस लौट जायें। लेकिन रावलपिंडी के हाल के धमाकों से राष्ट्रपति जिया की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि यह विपत्ति अल्लाहताला की ओर से आयी है। लोग कहते हैं कि बेशक अल्लाह की तरफ से यह कहर बरपा हुआ, लेकिन यह शासकों का फर्ज था कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय और प्रबंध करते। यदि तबाही और बर्बादी को सरकार नहीं रोक सकती, तो उसको सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिन नेताओं ने राष्ट्रपति जिया और प्रधानमंत्री जुनेजो से इस्तीफे की मांग की है उनमें बेनजीर भुट्टो, काजी हुसैन अहमद, मलिक काशिम, वली खां, गौस बख्श बिजेंजो, मौलाना फजलुर्रहमान, मेराज मोहम्मद खां आदि शामिल हैं।

—यूसुफ खान, इस्लामाबाद से

अमरीकी फर्म

राजीव के भविष्य का आकलन

लोकसभा के १९८९ में होनेवाले चुनावों में विपक्ष की सफलता की कितनी आशा है? दूसरे शब्दों में राजीव गांधी के पुनः सत्ता में आने की कितनी उम्मीद है? ऐसी बातों पर भविष्यवाणी करनेवाली अमरीकी एजेंसी कहती है कि विपक्ष की संभावना मात्र ३५ प्रतिशत है। क्या इसका मतलब है कि राजीव की सत्ता में वापसी की संभावना ६५ प्रतिशत की बुलंदी पर है?

'फ्रास्ट एंड सुलीवान' नामक यह निजी फर्म अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं देती। किंतु वह पहले का उत्तर अवश्य देती है। शायद इसका अर्थ है कि पहले प्रश्न के उत्तर से ही अंतिम प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। विपक्ष की हालत में सुधार क्यों हुआ है? एजेंसी की सूचनाओं के अनुसार गत चुनावों के बाद से शासक पार्टी के मुस्लिम और हरिजन-समर्थकों में कमी आयी है, जबकि इन्हीं समुदायों में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है।

'फ्रास्ट एंड सुलीवान' ने भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन इसलिए नहीं किया कि इसकी राजीव सरकार के भविष्य में दिलचस्पी है। दरअसल, फर्म का धंधा ऐसी अध्ययन रिपोर्टों को उन अमरीकी व्यवसायियों के हाथ बेचने से जुड़ा है, जिन्होंने पहले ही भारत में पूंजी लगा रखी है अथवा ऐसे पूंजी-निवेशों में जिनकी रुचि है। चतुर व्यवसायी किसी बाहरी देश में पूंजी लगाने के पूर्व उसके राजनीतिक भविष्य का भलीभांति आकलन कर लेना जरूरी समझते हैं।

किंतु, कोई सामान्य आदमी पूछ सकता है कि इससे व्यवसायियों को क्या फर्क पड़ता है कि सत्ता में विपक्ष आता है या राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस-इ? लेकिन वास्तव में फर्क पड़ता है। यह बात कम-से-कम जानकार लोगों के सामने गत साढ़े तीन वर्षों से स्पष्ट है। राजीव गांधी ने उदारतावाद की नीति अपनायी है। इस सिलसिले में सरकार ने निगम क्षेत्र को अनेक महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की हैं। इसके साथ-साथ विदेशी पूंजी निवेश के लिए खुले द्वार की नीति ही मानो अपना ली गयी थी। विदेशी पूंजी निवेश पर लागू प्रतिबंध को लगभग पूर्णतया वापस ले लिया गया है और विदेशी व्यवसायियों को अपने सामानों के लिए मनमानी कीमतें वसूलने की हरी झंडी दिखा दी गयी है।

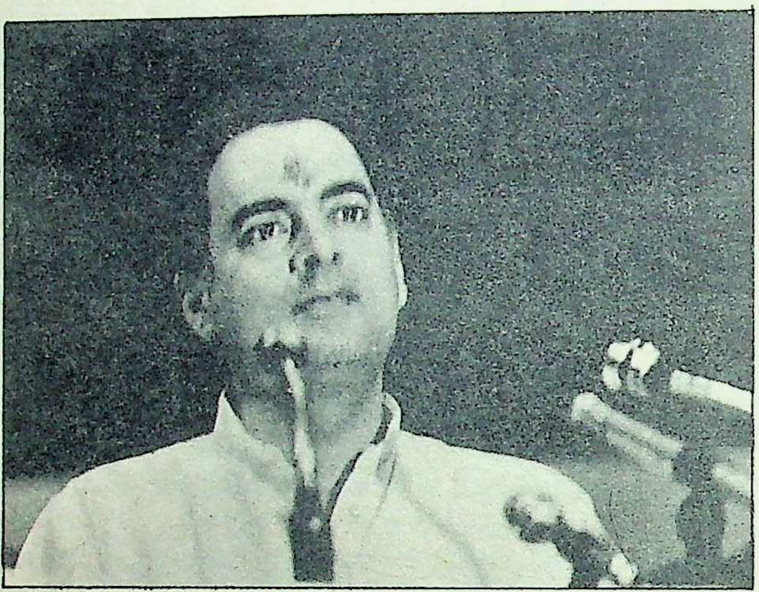

विदेशी पूंजी निवेशकों की रुचि : राजीव गांधी

सरकारी नीति का एक अहम पहलू यह भी है कि आबादी के किस भाग को अधिक सुविधाजन्य आय प्राप्त होनी चाहिए। यदि 'उच्च' या 'संपन्न' आय समूहवाले परिवारों को वही विशेष सुविधाएं जारी हैं जो पहले से थीं, तो उनकी आय मूल्यवृद्धि के बावजूद कम नहीं होगी। ऐसी हालत में अपनी आय का अधिक या काफी भाग वे ऐसी चीजों की खरीद में लगाने में समर्थ होंगे, जिन्हें केवल धनी लोग खरीदते हैं। ऐसे अनेक इलेक्ट्रानिक उपकरण हैं—मसलन—वीडियो, रंगीन टीवी, महंगे संगीत संयंत्र, स्कूटर या यात्री कार, महंगी प्रसाधन सामग्री अथवा नये किस्म के टेलीफ़ोन संयंत्र।

इसका अर्थ है कि इन सामानों की देश में मांग इतनी अधिक होगी कि उत्पादक भरपूर लाभ कमाकर इनकी सप्लाई कर सकेंगे। सरकार इन परिवारों के आयकर में कमी कर, महंगे टिकाऊ उपभोक्ता अथवा विलासिता के सामानों की खरीद के लिए आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कर या इन सामानों पर अधिक ऊंचा शुल्क या तटकर न लगाकर विदेशी व्यवसायियों की मदद कर सकती है।

विदेशी पूंजी निवेशकों का राजीव गांधी पर विश्वास दृढ़ हुआ है खासकर उनकी गत तीन वर्षों की आर्थिक नीति को लेकर। इसलिए राजीव गांधी सरकार का सत्ता में बने रहना, उन्हें पसंद है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। अमरीकी फर्म के अध्ययन और भविष्यवाणी ने इस प्रकार ऐसे अमरीकी व्यवसायियों और अप्रवासी भारतीय पूंजी-निवेशकों को पुनः आश्वस्त किया है जो भारतीय फर्मों से सहयोग संधि की बाट जोह रहे हैं।

फिर से छापा राज

राजस्व अधिकारियों के हाल
दो छापों ने उद्योगपतियों
हतप्रभ कर दिये हैं। ये छा
उद्योगपति विजय मलैया औ
फिक्की के पूर्व अध्यक्ष राम प्रसा
गोयनका के कार्यालयों और आवा
पर मारे गये थे। मलैया का भारती
निगम क्षेत्र में नया-नया दाखि
हुआ है। जबकि आरपी गोयनका
शीर्षस्थ उद्योगपतियों में से है
महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मा
पूर्व गोयनका के एक सवाल के जवा
में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था
कि वह वित्त मंत्री (तत्कालीन
विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहेंगे कि
वह औद्योगिक घरानों पर छापे बं
करें। राजधानी में यह चर्चा जोरों
पर है कि सरकार ने छापाराज पुन
शुरू कर दिया है। (उल्लेखनीय है
कि 'छापाराज' शब्द आर
गोयनका ने ही सर्वप्रथम इस्तेमा
किया था)। राजीव गांधी यह जता
को तत्पर लगते हैं कि वीपी सिंह
तरह वह भी अपराधी उद्योगपति
की धरपकड़ के लिए गंभीर हैं। इस
शासक दल जनता पर यह प्रभाव
डाल सकेगा कि वीपी सि
प्रधानमंत्री की इच्छा पर
औद्योगिक घरानों पर छापे डल
रहे थे। कांग्रेस-इ को आशंका है
वीपी सिंह यह प्रचार करेंगे
राजीव गांधी ने कर
उद्योगपतियों की धर पकड़ से
खींच लिया है। इसलिए दुबा
'छापाराज' चलाने से वीपी सिंह
प्रचार बेअसर हो जायेगा।

एक मत यह भी है
छापाराज का मकसद उन औद्योगि
घरानों को सबक सिखाना है जिन
गैरकांग्रेस राज्य सरकारों से मैत्री
संबंध हैं। यह मिथ्या प्रचार जोरों
से फैलाया गया था कि आर
गोयनका पश्चिम बंगाल के मुख्यमं
ज्योति बसु के बड़े करीबी हैं।
लोगों का तो यहां तक कहना है
गोयनका ने पंचायत चुनावों

आरपी गोयनका शीर्षस्थ उद्योगपतियों में से हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ माह पूर्व गोयनका के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि वह वित्तमंत्री (तत्कालीन) विश्वनाथ प्रताप सिह से कहेंगे कि वह औद्योगिक घरानों पर छापे बंद करें।

आरपी गोयनका

मार्क्सवादी पार्टी को अच्छा-खासा धन दिया था।

बंगलोर के उद्योगपति विजय मलैया पर आरोप है कि उनकी कर्नाटक की जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री हेगड़े से खूब छनती है। इसके अलावा उन्हें तमिलनाडु में सत्ता की दावेदार जयललिता का करीबी बताया जाता है।

एक और अफवाह भी गोयनका पर मारे गये छापों के सिलसिले में है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार था और राज्य सरकार और गोयनका दोनों ही इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रिलायंस उद्योग के धीरूभाई अंबानी गुजरात में पेट्रोकेमिकल्स का एक नया प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। इस परियोजना को विशाल पूंजी की जरूरत थी और सरकार के वित्तीय संस्थानों को हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स और प्रस्तावित गुजरात प्लांट में बड़ी मात्रा में कर्ज मुहैया करना पड़ता। यदि हल्दिया परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो धीरूभाई अंबानी का काम कई तरह से आसान हो जायेगा। एक, परियोजना के लिए कर्ज अधिक आसानी से मिल जायेगा और दूसरे, धीरूभाई के गुजरात प्लांट के उत्पाद का कोई प्रतिद्वंद्वी नही रह जायेगा।

शायद, प्रत्येक अफवाह में कुछ सचाई भी नजर आती है। गोयनका के कार्यालयों पर अनेक कारणों से छापे मारे गये, ऐसा लगता है। एक बात स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार हल्दिया परियोजना की कट्टर विरोधी है। कारण वह मार्क्सवादी पार्टी शासित एक राज्य है और वहां कांग्रेस-इ के निकट भविष्य में सत्तारूढ़ होने की आशा दूर-दूर तक नजर नहीं आती। यदि गोयनका को काली सूची में डाल दिया जाता है, तो यह बताना आसान होगा कि हल्दिया परियोजना को क्यों रद्द किया जा रहा है। यह भी जगजाहिर है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के विदा होने के बाद से धीरूभाई अंबानी राजीव सरकार के कृपा-पात्र बन गये हैं। यह बात भी है कि राजीव गांधी अपनी 'श्रीमान-स्वच्छ' की छवि वापस पाना चाहेंगे जो बोफोर्स घोटाले और वीपी सिंह के रहस्योद्घाटनों के बाद धुंधली पड़ गयी है।

—अर्थविज्ञानी

ऊह... आह... आउच को दूर भगाइए !

बदन दर्द और पीठ दर्द पर भी उसी तरह ध्यान देने की ज़रूरत है जैसे कि मोच, पेशियों में खिंचाव और जोड़ों की जकड़न पर.

इसलिए आयोडेक्स हमेशा अपने पास रखिए.

आयोडेक्स न सिर्फ़ दर्द से छुटकारा दिलाता है बल्कि चोट खायी कोशिकाओं को भी अच्छा करता है.

और आयोडेक्स दिन में दो बार मलें तो दुगुना फ़ायदा मिले.

इसलिए 'ऊह', 'आह' और 'आउच' को दूर भगाने के लिए आयोडेक्स लगाइए, और काम पर जाइए.

HTA 1711

आयोडेक्स®
मलिए,
काम पर चलिए.

SKF— एस के एफ़ का उत्पादन.

आये भी वे, गये भी वे

अमरीका आ रहे हैं या जा रहे हैं? अमरीकी व्यावसायिक घराना पेप्सीकोला भारत में धन लगाने को उत्सुक है और सरकार दुविधा में है कि उन्हें अनुमति दे या नहीं—वहीं अनेक अमरीकी कंपनियां सब कुछ बेच-बाचकर यहां से अलविदा हो रही हैं। ताजा विदा होनेवाली कंपनी है—कैसर्स, जो इस देश में वर्षों से जमी थी। पहले वह १९५० से टाटा की २० लाख टन इस्पात विस्तार योजना में सलाहकार के रूप में कार्यरत थी और बाद में बिड़ला के हिंदुस्तान अल्युमिनियम, (जो हाल तक की भारत की शायद सबसे मुनाफेवाली अल्युमिनियम कंपनी थी) की साझेदार के रूप में कार्यरत रही। रिपोर्टों के अनुसार कैसर्स अपना संपूर्ण २६ प्रतिशत इक्विटी साझा जो १३ करोड़ रुपए के लगभग है, आदित्य बिड़ला समूह के प्रबंधवाली बिड़ला कंपनी को बेच रही है। यह अमरीकी कंपनी एक अन्य बिड़ला कंपनी मैसूर सीमेंट से भी हाल में बाहर हो गयी है।

कैसर्स की भारत से वापसी का कारण उनकी यह नीति है कि संयुक्त व्यवसायों में अल्पसंख्यक भागीदार बनकर नहीं रहा जाये। उसने संभवतः यूरोप में भी ऐसे व्यवसायों से अपने को अलग कर लिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान अल्युमिनियम अपने मुनाफे की दृष्टि से पूरी तरह सरकार पर निर्भर है, क्योंकि कीमतें नयी दिल्ली से तय होती हैं। यह तथ्य ही कैसर्स और साथ ही अन्य अमरीकी कंपनियों के लिए कड़ुवा घूंट बन गया और उन्होंने यहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी।

रिलायंस की छलांग

वह कौन सी कंपनी है, जिसका दस वर्ष पूर्व अस्तित्व भी नहीं था, किंतु निगम क्षेत्र में छलांग लगाकर वह पहले नंबर पर पहुंच गयी है: वह कंपनी है, धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। दो वर्ष पूर्व रिलायंस की परिसंपत्तियां १०४६ करोड़ रुपए की थीं और सूची में उसका दूसरा स्थान था। तब पहले स्थान पर थी, टाटा स्टील कंपनी जो कम-से-कम ८० वर्षों से [illegible] और बनी हुई थी। गत वर्ष रिलायंस की परिसंपत्तियां सहसा दुगनी हो २००२ करोड़ पर पहुंच गयीं और उसने टाटा को शीर्ष से एक सीढ़ी नीचे कर दिया। उस समय टाटा स्टील की परिसंपत्तियां १४६० करोड़ रुपए की थी। टाटा की एक और भीमकाय कंपनी—टाटा इंजीनियरिंग, जो टेलको के नाम से जानी जाती है, तीसरे स्थान पर थी और उसकी परिसंपत्तियां १०२९ करोड़ रुपए की थीं।

धीरूभाई अपनी दुगनी परिसंपत्तियों के बलबूते चोटी पर तो जरूर पहुच गये हैं, किंतु इससे उनकी दक्षता और कुशलता में सुधार नहीं हुआ है। दिसंबर, १९८६, को समाप्त हुए वर्ष में रिलायंस के कुल मुनाफे में दो तिहाई कमी आयी और वह ६७ करोड़ रुपए से घटकर ६८ करोड़ रुपए हो गया और करों के बाद घटकर पांचवां भाग रह गया। यह सच है कि अनेक भीमकाय कंपनियों का मुनाफा भी १९८६ में गिर गया था, किंतु रिलायंस अपने मुनाफों में हुई कमी के झटके से अभी तक उबर नहीं पाया है। बहरहाल, इससे अंबानी पस्त नहीं हुए हैं। गत सप्ताह ही उन्हें बड़ौदा में अपने १५०० रुपए के नये प्लांट-पेट्रोकेमिकल्स कांप्लेक्स—को स्थापित करने की अनुमति मिल गयी है। यह अवश्य है कि यह प्लांट एक अलग कंपनी के अंतर्गत काम करेगा अपराजेय रिलायंस के नहीं। अंबानी को अपने सर्वोच्च स्थान से तभी हटाया जा सकता है, जब टाटा स्टील अपनी इस्पात क्षमता में छलांग भरकर १० लाख टन का इजाफा करे, जिसके लिए सरकार टाटा पर दबाव डाल रही है, किंतु इसमें भी काफी समय लगेगा।

धीरूभाई अंबानी

बिड़ला समूह का वर्चस्व

समूह के रूप में रिलायंस अभी भी बिड़लाओं से पीछे है और टाटा १९८४ से दूसरे नंबर पर हो गये हैं। रिलायंस तीसरे नंबर पर है और टाटा से उनकी परिसंपत्तियां आधी हैं. गोकि पांच वर्ष पूर्व टाटा की परिसंपत्तियां रिलायंस से पांच गुना ज्यादा थीं। चौथे नबरवाले औद्योगिक समूह सिघानियाओं को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। वैसे, अन्य की तुलना में उसकी प्रगति बेहतर है। १९८३ और १९८६ के बीच केवल दो बाहरी कंपनियां—मद्रास की चिदंबरम और बंबई की बजाज-शीर्ष दस कंपनियों में अपना स्थान बना पायी हैं। चिदंबरम जो दसवें नंबर के आसपास रहा करती थी, वह दक्षिण की भीमकाय कंपनी स्पिक को अधिग्रहण करने के बाद उछलकर एक सीढ़ी ऊपर ९ नंबर पर षहुंच गयी है।

घनश्याम दास बिड़ला

व्यावसायिक घराने के रूप में चिदंबरम के अलावा तेजी से फलने-फूलने वाली कलकत्ता के खेतान की मैकनील ऐंड मैगोरक्स है, जिसने १९८३ से अपनी पग्रिसंपत्त्यियों में करीब तीन गुनी वृद्धि की है। इसकी तरक्की की रफ्तार रिलायंस के समान है और टाटाओं-बिड़लाओं से तीन गुना अधिक है। खेतान ने जिन कंपनियों को हासिल किया है, अभी उन्हें चुस्त-दुरुस्त करना शेष है, क्योंकि उनमें से कुछ मसलन मेटल बाक्स उसके लिए सिरदर्द है।

टाटा में फेरबदल

टाटा की कुछ कंपनियों में फेरबदल होने जा रहा है। ऐसी अफवाह है कि टाटा स्टील के गत पांच वर्षों से अध्यक्ष रहनेवाले और इसे टाटा
कंपनियों की सोने की
बनानेवाले रूसी मोदी
इंजीनियरिंग (टेल्को) के चेयर
बननेवाले हैं, गोकि मोदी ने खुद
रिपोर्टों का खंडन किया है। टेल्को
पल्लवित पुष्पित करनेवाले
मुलगांवकर एक टेक्नोक्रैट हैं जो
की ही कंपनी एसोसिएटेड सीमें
टेल्को में चालीस वर्ष पूर्व आये
और इसे भारत की सर्वो
इंजीनियरिंग कंपनी में बदल
था। मुलगांवकर कुछ समय
बीमार हैं और पदमुक्त होना चाहते
बताया जाता है कि मोदी को,
टेल्को के निदेशक हैं, स्थायी चेयरमै
की व्यवस्था होने तक कंपनी
कार्यभार संभालने को कहा गया है

टेल्को की प्रगति कुछ वर्षों
बहुत संतोषजनक नहीं, क्योंकि
उद्योग में नयी कंपनियों के आगमन
से प्रतिद्वंद्विता बढ़ गयी है। टेल्को का
मुनाफा १९८६ में १५ करोड़ की
जगह गिरकर ५.८ करोड़ पर आ
गया था, किंतु तब से कुछ सुधार हुआ
है। उसका सितारा फिर बुलंद हो
सकता है, बशर्ते उसकी यात्री कार
परियोजना को हरी झंडी मिल जाये
कंपनी कई वर्षों से २ लाख रुपए के
बीच की कीमत की एक ऐसी का
बनाने की सोच रही है जो पूरी तरह
उसकी अपनी तकनीक पर निर्मि
होगी, किंतु दिल्ली ने इस पर कोई
दिलचस्पी नहीं दिखायी थी
इसीलिए इस क्षेत्र में मोदी के प्रवेश के
आसार नजर आ रहे हैं। मोदी का
तुरुप का पत्ता है, गांधी परिवार
उनका संबंध और टाटा मोदी
पत्ता खेलने के इच्छुक हो सकते हैं

परियोजना के लिए रस्साकशी

एच बी जे गैस पाइप ला
परियोजनाओं का क्या हाल है
कम-से-कम दो पार्टियों—स्वरा
पाल और टाटा ने उससे हाथ
लिया है। गोकि दोनों का मानना
कि उनकी दिलचस्पी कम नहीं है
अब एक अन्य परियोजना के
रस्साकशी जारी है: सलीमपुर
१००० करोड़ की पैट्रोकेमि
परियोजना जो एक समय बंबई
रिलायंस के हाथों जाते-जाते रह
थी और जिसे पुनः हथियाने की
कोशिश कर रहा है।

सलीमपुर एरोमैटिक्स परियोजना का आशयपत्र मूलतः प्रदेशीय इंडस्ट्रियल कारपोरेशन आफ यूपी (पीआईसीयूपी) को १९८६ के आरंभ में जारी हुआ था। पीआईसीयूपी ने विशेष प्रगति नहीं दिखायी और आशयपत्र गत वर्ष के आरंभ में समाप्त हो गया। पीआईसीयूपी कांप्लेक्स को संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए रिलायंस से सहयोग करने को इच्छुक बताया जाता था, किंतु रिलायंस ऐसा समान अवसर अपने गृहनगर के पास पाना चाहता था जो उसे अब हासिल हो गया लगता है। उसने गुजरात पैट्रोकेमिकल कांप्लेक्स से सहयोग करने का फैसला कर लिया है और सलीमपुर से अलग हो गया है। पीआईसीयूपी अब साझेदार की तलाश में है। इस सिलसिले में जो दो नाम लिये जा रहे हैं, वह हैं, इफ्को और क्रिमको। इन दोनों के कार्य व प्रगति-रिकार्ड और बैंक एकाउंट्स बहुत संतोषजनक हैं। सूची की दूसरी कंपनियां हैं, आईपीसीएल और जे के सिंथेटिक्स। आईपीसीएल के पास पहले ही दो कांप्लेक्स हैं—एक बड़ौदा में और दूसरा बंबई में जे के सिंथेटिक्स ऐसी परियोजना की प्राप्ति के लिए इच्छुक था।

सलीमपुर परियोजना बेनजीन पर आधारित एक एरोमैटिक्स कांप्लेक्स होगा, जबकि अन्य पैट्रोकेमिकल्स कांप्लेक्स इथिलीन पर आधारित होते हैं। यह उत्तर भारत की अपने तरह की पहली परियोजना होगी।

घाटे का चक्रव्यूह

कलकत्ता की बीमार बहुराष्ट्रीय कंपनी गेस्ट कीन विलियम्स पुनः सिरमौर-विहीन हो गयी है। केके बिड़ला की कभी इस कंपनी में दिलचस्पी थी और कहा जाता है कि उन्होंने उसके ६ प्रतिशत इक्विटी शेयर भी खरीदे थे। किंतु उन्होंने उसके बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया है। टाटा ने भी एक समय कंपनी में रुचि ली थी, किंतु बिड़ला ने उन्हें पीछे हटा दिया था। अब दोनों तस्वीर से बाहर हैं और कंपनी चक्रव्यूह में है।

गेस्ट कीन गत दो वर्षों से घाटे में चल रही है। एक समय अफवाह थी कि इसका नियंत्रण करनेवाला समूह नेटलफोल्ड उससे अलग होना चाहता है। बिड़ला की अपने समूह की कंपनी टेक्समाको की वजह से उसमें दिलचस्पी थी। वह चाहते थे कि उसकी क्षमता का उपयोग वह अपने व्यवसाय के लिए करें। टाटा स्टील ने एक समय अपने अध्यक्ष के के ईरानी को गेस्ट कीन बोर्ड में नियुक्त करा दिया था, किंतु यह बिड़लाओं के आगमन के पहले की बात है। कंपनी में श्रमिकों की अधिकता के होने और परिवर्तित व्यावसायिक दृश्य के अनुकूल अपने को ढालने और लाभ कमाने में अक्षम होने की बात कही जाती है। इसकी अंडूल स्थित फाउंड्री गत कुछ महीनों से बंद पड़ी है। यदि नेटलफोल्ड समूह प्रबंध व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं करेगा, तो कंपनी से अधिग्रहण का शिकार हो जायेगी।

सरगम का सौदा

इस बीच राम प्रसाद गोयनका व मनु छाबड़िया ने सहयोग के लिए एक नया क्षेत्र चुन लिया है। उधर अफवाहें जारी हैं कि दोनों शीर्ष उद्योगपतियों के संबंध पूरी तरह मधुर नहीं हैं। दोनों ने कलकत्ता में कमपैक्ट डिस्क बनाने की एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। यह डिस्क हाई-फाई संगीत प्रेमियों की ताजा ललक है। इसे कनाडा के एस एन सी के सहयोग से भारत में बनाया जायेगा। इसकी बिक्री भारत में एच एम वी करेगी (जो गोयनका की एक कंपनी है) और खाड़ी के देशों में छाबड़िया की कंपनी। इस परियोजना पर लगभग १० करोड़ की लागत आयेगी।

एच एम वी ने खुद भारतीय संगीत सहित कम्पैक्ट डिस्क की बिक्री शुरू कर दी है, यद्यपि डिस्क आयातित हैं। कम्पैक्ट डिस्क रिकार्ड प्लेयर्स बनाने का एक प्रस्ताव भी है जो पूर्णतया छाबड़िया की परियोजना हो सकती है। छाबड़िया के जापान के सोनी से अच्छे संबंध हैं। इसी कारण खाड़ी के देशों में सबसे पहले यह व्यवसाय शुरू किया गया। भारतीय संगीत की विदेशी बाजारों में खासी मांग है। अमरीका में भारतीय संगीत युक्त कम्पैक्ट डिस्क की बिक्री करनेवाली एक कंपनी एम एम वी और अन्य रिकार्डिंग कंपनियों को थोड़ी रायल्टी देती है।

—जय दुबाशी

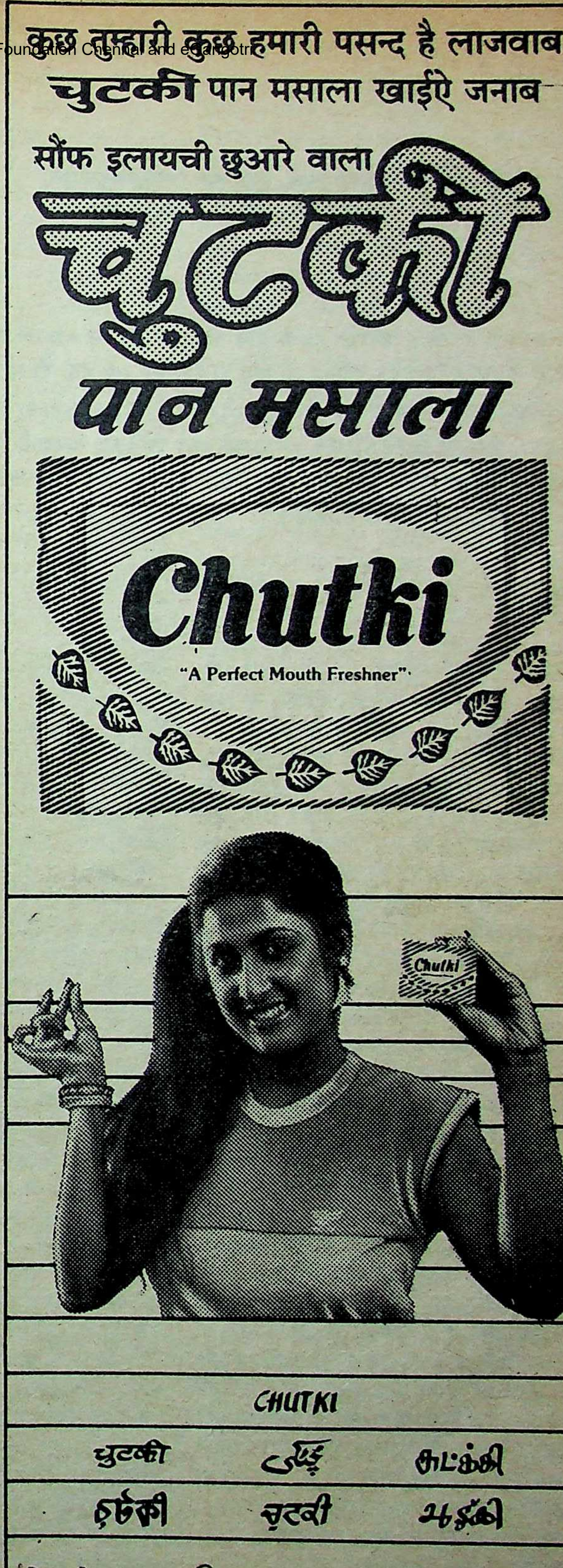
कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब
चुटकी पान मसाला खाईऐ जनाब
सौंफ इलायची छुआरे वाला
चुटकी
पान मसाला
Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"
Chutki
CHUTKI
चुटकी
छटकी
चुटकी
के॰के॰ कार्यालय का उत्कृष्ट उत्पादन

महाराष्ट्र का दवा घोटाला

दवा के नाम पर जहर

२४ जनवरी '८६ से ८ फरवरी '८६ के बीच बंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नकली दवाओं के कारण जिन १४ रोगियों की मृत्यु हो गयी थी, उस कांड की जांच बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी लेंटिन ने की। ३०१ दिनों की जांच के बाद बी लेंटिन ने जो २८९ पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की, उसको मद्दे नजर रखते हुए मुख्यमंत्री चह्वाण ने स्वास्थ्य मंत्री भाई सांवत की छुट्टी कर दी है। लेकिन क्या यह मामला यहीं समाप्त हो गया? आगे की जांच क्या गुल खिला सकती है?

जिंदगी से खिलवाड़ : बलीराम हिरे

लगता है जैसे महाराष्ट्र की राजनीति पर घोटालों एवं न्यायदंड का राहु लग गया है। अब्दुल रहमान अंतुले तथा शिवाजी राव पाटील-निलंगेकर को इन्हीं आरोपों में गद्दी गंवानी पड़ी। रामराव आदिक तथा और कई मंत्रियों को अपने पदों से हटना पड़ा। महाराष्ट्र के कई वर्तमान मंत्रियों, विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं के विरुद्ध घोटालों के आरोप हैं। अब गाज गिरी है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भाई दास सावंत तथा डा० बलीराम हिरे पर। गत ३० मार्च को लेंटिन रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में उनके विरुद्ध न्यायिक जांच कराने की घोषणा की गयी।

पृष्ठभूमि : २४ जनवरी '८६ से ८ फरवरी ८६ के बीच ब्रंबई के सरकारी अस्पताल, जिसकी गणना एशिया के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में की जाती है, में नकली दवाओं के कारण १४ रोगियों (अनधिकृत सूचना के अनुसार ४७ से भी अधिक) की अकाल मौत हो गयी थी। इस कांड की जांच के लिए २२ जून, १९८६ से बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बख्तावर लेंटिन ने न्यायिक जांच शुरू की। ३०१ दिनों की बैठकों के बाद उन्होंने २८९ पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण को सौंप दी। रिपोर्ट के साथ लोहे के तीन बक्सों में सबूत भी उन्होंने सरकार को सौंप दिये। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे पांच महीने तक रिपोर्ट को दबाये रखने के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर उसके कुछ अंशों को ३० मार्च '८८ को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया। ज्ञात हो कि लेंटिन आयोग ने अपनी जांच के बाद इन दो मंत्रियों के अलावा अन्य विभागों के कई अधिकारियों को प्राथमिक दृष्टि में दोषी पाया। इन विभागों में से एक भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो भी है। सरकार ने आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की तलाश शुरू कर दी है, जो इन मंत्रियों और अधिकारियों की जांच करेगा।

रिपोर्ट के सदन में रखे जाने से पहले १० मार्च, १९८८ को स्वास्थ्य मंत्री भाई दास सावंत ने, मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्याग पत्र दे दिया था, मुख्यमंत्री को आशंका थी कि श्री सावंत के इस्तीफा न दिये जाने पर विधानसभा अधिवेशन में काफी हंगामा होगा और विपक्षी दलों ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी।

आयोग की सिफारिशें : लेंटिन आयोग ने अपनी सिफारिशों को पांच हिस्सों में बांटा है। प्रथम हिस्से में उन्होंने दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों (डा० बलीराम हिरे तथा भाई दास सावंत) के विरुद्ध उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जांच कराने तथा इस कांड के लिए जिम्मेदार १० सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा जेजे अस्पताल को नकली दवाएं देने वाली कंपनियों के मालिकों—एचएम केमिकल्स के महेंद्र और गिरीश दोषी, कैलाश कंपनी के गिरिधर एवं भारत कासट तथा अल्पना फार्मा के ओमप्रकाश लड्ढा के विरुद्ध औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के तहत तुरंत एवं तीव्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

दूसरे हिस्से में जेजे अस्पताल में अधिष्ठाता (प्रशासन) तथा डीन (चिकित्सा) के पद को अलग कर उन पर निर्भीक, ईमानदार तथा निष्ठावान योग्य व्यक्तियों की पूर्णकालिक नियुक्ति, करने की बात कही गयी है। तीसरे हिस्से में दवा खरीदी के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को दी गयी आरक्षण-सुविधा को समाप्त करने की सिफारिश है, चौथे हिस्से में खाद्यान्न व औषधि प्रशासन तथा सरकारी विश्लेषण प्रयोगशालाओं को चुस्त-दुरुस्त एवं बाहरी दवाओं को मंत्रियों की दखलंदाज़ी से मुक्त रखने और पांचवें हिस्से में मृतकों के परिजनों को दस हजार रुपए के अलावा २० हजार रुपए तुरंत देने की सिफारिश की गयी है। इसके साथ ही यह भी सिफारिश की गयी है कि यदि नकली दवाओं के कारण १४ व्यक्तियों के अलावा और भी रोगियों की मौत हुई हो, तो उनके भी परिजनों को ३०-३० हजार रुपए अतिरिक्त दिये जायें।

आयोग के सामने सिर्फ १४ मृतकों के
पेश हुए थे। सरकार ने ८० गवाह पेश किये,
आयोग ने १८ और गवाहों के बयान सुने।
कुल ३७३२ पृष्ठ की गवाहियां दर्ज कीं। इस
दौरान ३८७ फाइलें एवं दस्तावेज जब्त किये
थे। आयोग के सामने २४२४ फाइलें और
पेश किये गये थे, जबकि बहुत से रिकार्ड
दस्तावेज गायब पाये गये थे। सुनवाई के
आयोग ने सरकारी वकील मोरे और
इंस्पेक्टर एनएस निकम की खिचाई करते
टिप्पणी की थी, "इससे मुझे तो संदेह होने
क्या मैं यह मान लूं कि वे ही पेपर आयोग के
पेश किये गये हैं जो आपके लिए सुविधाजनक
किसके आदेश पर आपने इन्हें पेश नहीं किया?
मैं यह भी मान लूं कि सरकारी वकील के
ये दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिन्हें ११ जून
पेश किया जाना चाहिए था?" सीआईडी
ने यह भी कहा कि आर्डर बुक नं० १ और ३
अस्पताल में पड़ी रह गयी हैं, जबकि जेजे
के डीन ने लिखित सूचना दी थी कि इस
संबंधित सारे दस्तावेज दे दिये गये हैं
अस्पताल में कुछ भी शेष नहीं है। कई
सरकारी अधिकारियों ने अपनी गवाहियों
आयोग को बरगलाने की भी कोशिश की थी।
बार जब सरकारी वकील ने मूल आर्डर
सील-बंद होने की बात कह कर टालने की
की थी, तो न्यायाधीश लेंटिन ने तुरंत
जेरोक्स प्रतियां निकाल कर आयोग के
करने का निर्देश दिया था।

आयोग ने दोनों मंत्रियों के साथ-साथ
आरडी कुलकर्णी, वीसी साने, एसडी भिरुद,
देशमुख तथा एनडी कुलकर्णी के विरुद्ध उचित
के बाद भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो अथवा इसी
के सक्षम एवं उपयुक्त जांच अधिकारी से तह
कराने के लिए भी कहा। रिपोर्ट के पहले
तीन संस्थानों के जिन अधिकारियों को
कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच

सिफारिश की गयी थी, उनके नाम हैं—जेजे अस्पताल के डीन डा० आरएस चंद्रिकापुरे, अधीक्षक बीजी देशमुख, फार्माकोलोजी विभाग के प्रोफेसर डा० एसवी शालिग्राम तथा औषधि विशेषज्ञ एके जमदाग्नि (सभी जेजे अस्पताल), उद्योग विभाग के सहायक संचालक एसबी सातलकर, संयुक्त सचिव एनडी धारप तथा उद्योग अधिकारी पीके तोरवी (सभी उद्योग विभाग), संयुक्त आयुक्त शंकर महादेव डोलास, सहायक आयुक्त पीके कोचर तथा सहायक आयुक्त बीके विजमवार (सभी अन्न एवं औषधि प्रशासन) इनमें से बीसी साने तथा एसडी भिरुद बतौर आयुक्त तथा वीडी देशमुख एवं एनडी कुलकर्णी सह-आयुक्त के पद से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। डा० आरडी कुलकर्णी औषधिशास्त्र के प्रोफेसर पद से पहले ही हट चुके हैं।

महाराष्ट्र के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री प्रो० राम मेघे ने मार्च को विधानसभा में लेंटिन आयोग की रपट के साथ ११ पृष्ठों का स्पष्टीकरण भी दिया था। (इसमें सरकारी कार्रवाई का ब्योरा था)। उन्होंने बतलाया, "दोनों भूतपूर्व मंत्रियों की जांच के लिए हमने उपयुक्त न्यायाधीशों की तलाश शुरू कर दी है, शेष पांचों अधिकारियों के विरुद्ध जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दी है। जांच ब्यूरो इन पांचों के अलावा सभी संबंधित अधिकारियों की भी जांच कर रहा है। इनमें से श्री सातलकर, धारण तथा तोरवी के विरुद्ध विभागीय जांच भी चलेगी। उन्होंने सदन में यह भी कहा कि भाई सावंत मंत्री बनने लायक नहीं थे।

जेजे अस्पताल को नकली दवाओं की आपूर्ति करने वाली औषधि निर्माता एवं वितरक संस्थाओं के विरुद्ध राज्य सरकार अदालत में शीघ्र ही भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४ (हत्या के दोषी) व ३०४-ए तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की धारा-२७ के तहत मुकदमा दायर करेगी। इनके विरुद्ध धारा-३३८ (रोगियों को ग्लिसराल के इंजेक्शन से गंभीर असर होने) तथा मृत्यु के अन्य मामलों के बारे में भी विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज करने का निश्चय किया है। इसके अलावा मेसर्स केम सहित उन सभी सार्वजनिक विश्लेषण प्रयोगशालाओं के लाइसेंस एवं मान्यताएं रद्द कर देने का फैसला किया है जो औषधि निर्माताओं को झूठे प्रमाणपत्र दिया करती थीं।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा तथा औषधि विभाग के सचिवों की अध्यक्षता में समितियों का गठन कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तुरंत विभागीय जांच करने का भी निर्देश दे दिया है। इस समिति में योजना वित्त (व्यय) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधियों के अलावा चिकित्सा सेवा के संचालक तथा चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता और सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

प्रो० राम मेघे के अनुसार, "आयोग की सिफारिशों के अनुसार जेजे अस्पताल के तत्कालीन डीन डा० आरएस चंद्रिकापुरे, अधीक्षक बीजी देशमुख, डा० शालिग्राम तथा डा० एके जमदाग्नि को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है। औषधिशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका डा० (श्रीमती) वर्लीकर के कार्यकलापों की भी जांच की जायेगी। डा० जमदाग्नि पर जेजे अस्पताल को मिलावटी ग्लिसराल की आपूर्ति करने वाली अल्पना फार्मा से बतौर कमीशन ११ प्रतिशत से अधिक मांग करने का भी आरोप है।

न्यायाधीश लेंटिन ने सुनवाई के दौरान पूर्व स्वास्थ्यमंत्री भाई दास सावंत तथा खाद्यान्न एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त एसएम डोलास की काफी खिंचाई की थी। एक बार तो उन्होंने फूड ऐंड ड्रग्ज एडमिनिस्ट्रेशन (खाद्यान्न एवं औषधि प्रशासन) को 'फादर डोलास एडमिनिस्ट्रेशन' की संज्ञा दे दी थी। बंबई के एक अंग्रेजी दैनिक 'टाइम्स आफ इंडिया' ने डोलास को 'फ्रेंड्स आफ ड्रग एडल्ट्रेटर्स' का भी शीर्षक दिया था।

सावंत के खिलाफ आरोप: न्यायाधीश लेंटिन ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भाई दास सावंत को भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग तथा कर्तव्यपालन में चूक का दोषी ठहराते हुए उन्हें 'मंत्री बने रहने के अयोग्य' ठहराया। उन्होंने उन पर जो गंभीर १६ आरोप लगाये हैं, उनमें से प्रमुख हैं—जानबूझकर विरोधाभासों से भरपूर झूठी गवाहियां, मंत्री के रूप में सत्ता व अधिकारों का दुरुपयोग, खास अधिकारियों पर अनुचित अनुग्रह तथा असुविधाजनक अधिकारियों को परेशान करने के लिए 'स्थानांतरण हथियार' का गलत उपयोग, चार वरिष्ठ अधिकारियों के दावे तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय व आयुक्त के कड़े विरोध के बावजूद एसएम डोलास को बिना क्रम के अनावश्यक पदोन्नति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के

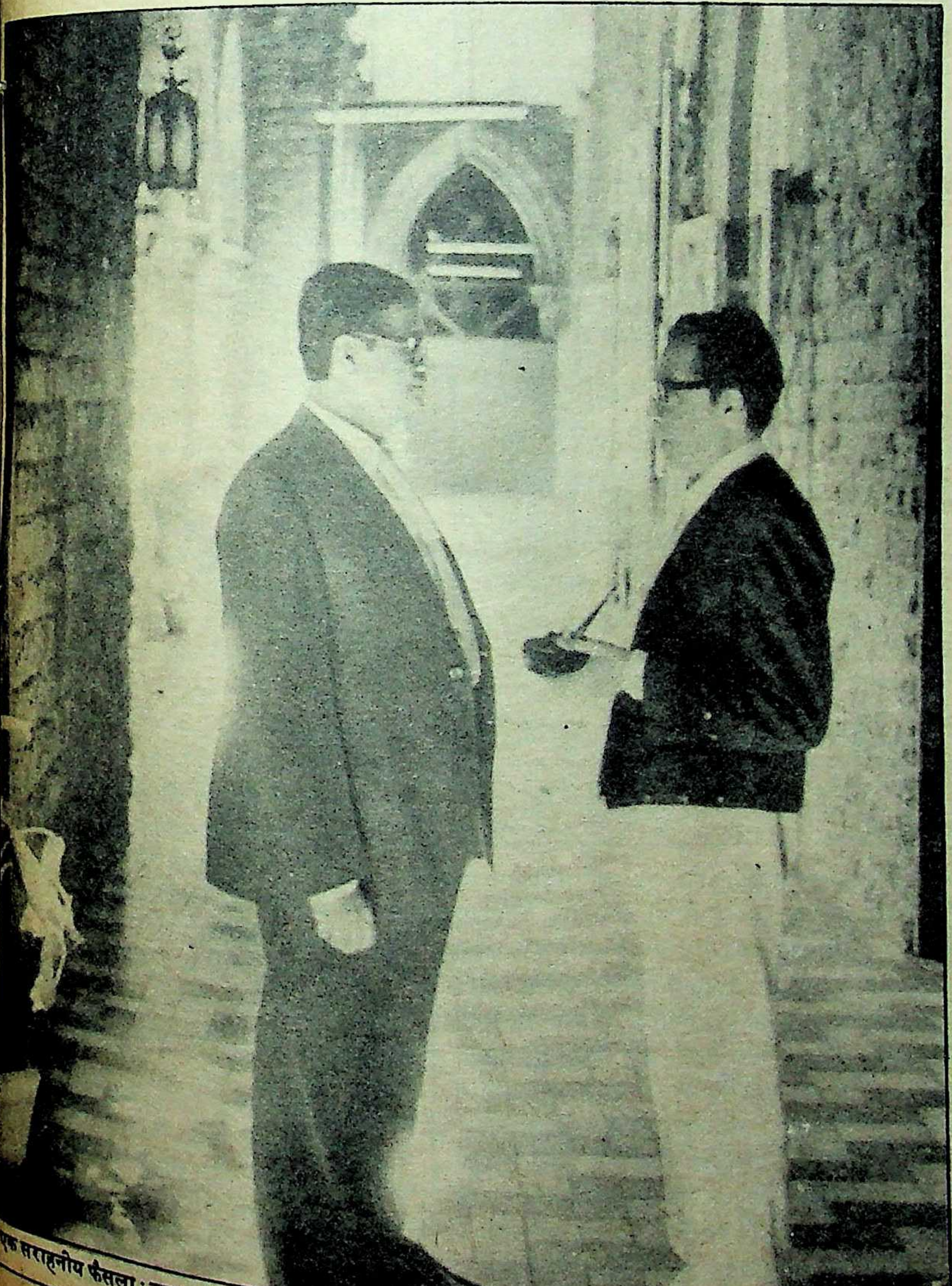

एक सराहनीय फैसला : न्यायाधीश लेंटिन (बायें) मुख्य न्यायाधीश चित्ततोष मुकर्जी के साथ

आदेश को ताक पर रख कर उस फर्म को लाइसेंस देना, जो घटिया गुणवत्तावाली जीवनरक्षक दवाओं का निर्माण करती थी, ग्रामीण उत्थान संगठन (आरयूओ) के लिए दान व विज्ञापन एकत्र करने के लिए मंत्रिपद का दुरुपयोग, आयोग की सुनवाई के दौरान एसडी भिरुद, डा० आरडी कुलकर्णी तथा रायकर पर अपने अनुकूल गवाहियां देने के लिए अनुचित दबाव, एसडी पाटील तथा एसएम डोलास को अनुचित संरक्षण देने के साथ उनके मामलों में जनता तथा आयोग को धोखा देने की कोशिश, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्ति को खुद हथिया लेने तथा इस मामले में आयुक्त को दरकिनार कर साधारण अधीक्षक से सलाह लेकर आयुक्त पद की गरिमा घटा देने की कोशिश, समर्थ फार्मास्युटिकल कंपनियों से सौदा तय कराने में अपने पद का दुरुपयोग, एसडी भिरुद, एसएम डोलास आदि अधिकारियों को अपने काबू में करके खाद्य औषधि प्रशासन के समूचे अधिकारी-वर्ग का मनोबल गिराने की प्रवृत्ति , अपने खिलाफ सबूतों को झूठा साबित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर उनके विरुद्ध साजिश रचने के गलत आरोप, अपने विभाग में घट रही घटनाओं तथा महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पूरी जानकारी न रखकर कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों की अवहेलना।

न्यायाधीश लेंटिन ने यद्यपि भाई दास सावंत को जेजे हत्याकांड में सीधे दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि उनके ऊपर लगाये गये ये आक्षेप काफी गंभीर थे। इसके विपरीत श्री सावंत ने इसे पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण आरोप की संज्ञा दी। ३० मार्च को ही उन्होंने विधानपरिषद में २२ पृष्ठों का अपना बयान जारी करके कहा, "आयोग ने न केवल उन पर निहायत बेबुनियाद, बल्कि झूठे, मौखिक प्रमाणों एवं पूर्वाग्रह से प्रेरित साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। आयोग ने सबूतों की न तो निष्पक्ष जांच की और न ही दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने का उन्हें मौका दिया।" श्री सावंत ने आयोग पर सुनवाई के दौरान जन-प्रतिनिधियों का अपमान करने का लांछन लगाते हुए वरिष्ठ सरकारी वकील द्वारा अपने (स्वास्थ्यमंत्री) नाम लिखा गया वह पत्र भी सदन में पेश किया, जिसमें वकील ने लिखा था कि न्यायाधीश पहले से ही उच्च सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों को दोषी ठहराने का मन बना चुके थे। आयोग की इस कार्यशैली के विरोध में वह (वकील) इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। (बाद में उक्त वकील ने इस्तीफा दे दिया था।) अधिकारियों के अनुचित स्थानांतरण के मामले में श्री सावंत का कहना था कि इनमें से बहुत से तबादले भूतपूर्व स्वास्थ्यमंत्री श्रीमती ललिता राव के आदेश से हुए थे। भ्रष्टाचार एवं स्थानांतरण से संबंधित जितने भी और जिस अवधि के सबूत पेश किये गये, उस समय श्रीमती राव कैबिनेट मंत्री तथा वह राज्यमंत्री थे। उन्होंने इस पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि आयोग ने श्रीमती ललिता राव को न केवल पूरी तरह से जांच से दूर रखा, बल्कि उन्हें (श्रीमती राव) छोड़कर पिछले १२—१५ वर्षों में जितने भी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन सभी को भ्रष्ट एवं निकम्मा ठहराया। आयोग का रवैया शुरू से ही मेरे खिलाफ था। वह मुझे दोषी साबित करने पर आमादा था। इस कार्य में जिन अधिकारियों ने आयोग की मदद की, उन्हें संरक्षण दिया गया। यदि किसी भी गलती के लिए कोई मेरे नाम का उल्लेख करता, तो आयोग बड़ी तत्परता से उस अधिकारी को संरक्षण देता था।

भाई दास सावंत

> आयोग ने न केवल उन पर निहायत बेबुनियाद, बल्कि झूठे, मौखिक प्रमाणों एवं पूर्वाग्रह से प्रेरित साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। आयोग ने सबूतों की न तो निष्पक्ष जांच की और न ही दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने का उन्हें मौका दिया। आयोग का रवैया शुरू से ही मेरे खिलाफ था। वह मुझे दोषी साबित करने पर आमादा था। इस कार्य में जिन अधिकारियों ने आयोग की मदद की, उन्हें संरक्षण दिया गया। यदि किसी भी गलती के लिए कोई मेरे नाम का उल्लेख करता, तो आयोग बड़ी तत्परता से उस अधिकारी को संरक्षण देता था।

आयोग की सुनवाई के दौरान तीनों भूतपूर्व स्वास्थ्यमंत्रियों (डा० बलीराम हिरे, गोविंद राव सरनायक तथा भाई दास सावंत) के मंत्रिपद के दुरुपयोग एवं पक्षपातपूर्ण मामले पेश हुए थे। डा० हिरे पर लगे महत्वपूर्ण आरोप थे—उन्होंने एक बदनाम औषधिनिर्माता जेजे तोलिया, जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा औषधि निर्माताओं के महत्वपूर्ण सेतु का भी काम करता था, को घटिया दर्जे की जिक आक्साइड की आपूर्ति करने के आरोप से बरी कर दिया था। डा० हिरे ने अपने पिता के नाम से स्थापित एक प्रायवेट ट्रस्ट के लिए धन एकत्र करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। १९८१ में मद्य निषेध एवं स्वास्थ्यमंत्री बनने के बावजूद वह उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने २०० से भी अधिक डिस्टलरियों, औषधि निर्माताओं तथा दूसरी यूनिटों से उक्त ट्रस्ट के लिए दान लिये। पूर्व स्वास्थ्यमंत्री श्री सरनायक पर भी इसी तरह के आरोप थे। आरोप के बारे में उनके असहयोग पूर्व रवैये पर झुंझला कर एक बार न्यायमूर्ति लेंटिन ने कहा था, "मैं यहां कोई नर्सरी नहीं चला रहा। अगर वह नहीं समझना चाहते, तो वह नहीं ही समझेंगे। मुझे तो यह जान कर अचरज होता है कि वह स्वास्थ्यमंत्री रह चुके हैं।"

श्री लेंटिन सुनवाई के दौरान खाद्य व औषधि प्रशासन के औषधि नियंत्रण लेबोरेटरीज का मुआयना कर काफी क्षुब्ध हुए थे और मैन रजिस्टर को उन्होंने 'मर्डर बुक' की संज्ञा प्रदान की थी। उन्हें यह देखकर हैरत हुई थी कि इंस्पेक्टरों द्वारा पास की गयी २० प्रतिशत दवाएं या तो नकली थीं या घटिया दर्जे की थीं।

जेजे अस्पताल में नकली ग्लिसराल के कारण पहली मौत २१ जनवरी, १९८६ को बापू थोरे की तथा अंतिम मौत दाऊद ढोलकिया (७ फरवरी '८६) की हुई थी। दवा के संबंध में ध्यान देने योग्य यह भी है कि इस दवा को बनानेवाला व्यक्ति रसायन शास्त्र में स्नातक था और दवा को स्तरीय होने का प्रमाणपत्र भी मिला हुआ था। इस अवधि के भीतर तथा बाद में कितनी मौतें हुई थीं, इसका महज अनुमान भर है, क्योंकि निलंगेकर प्रशासन तब तक इस मामले पर परदा डालता रहा, जब तक कि बेटी चंद्रकला निलंगेकर के अंक-घोटाले के कारण उनकी कुरसी नहीं चली गयी।

शंकर राव चह्वाण ने मार्च १९८६ में मुख्यमंत्री पद संभालने के चार महीने के भीतर लेंटिन जांच आयोग की स्थापना कर लोकप्रियता की पहली सीढ़ी हासिल की थी। १० मार्च '८८ को भाई दास सावंत से इस्तीफा मांग कर, ३० मार्च '८८ को लेंटिन आयोग की रपट विधानसभा में पेश कर एवं आयोग की सिफारिशों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करवाने का निर्णय कर अपनी सत्ता पर आये सबसे बड़े संकट को विधानसभा में इस मामले को लेकर होने वाले संभावित हंगामे को बड़ी चतुराई से टाल दिया, लेकिन विधायक केशव राव ढोंडगे के विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हुई चर्चा व इस्तीफा देने के बाद श्री सावंत के सदन में दिये गये भाषण में न्यायाधीश लेंटिन पर पक्षपात और पूर्वग्रह के जो आरोप लगाये गये हैं, उनसे न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

—रवीन्द्र

Tulsi
ZAFRANI ZARDA
FLAVOURED
CHEWING
TOBACCO
00
DHARAMPAL SATYAPAL
THE ECO
NO 116
ence
res
शानो शौकत के ढंग... तुलसी ज़र्दे के संग
अनेकानेक वैरायटीज़ में उपलब्ध
धर्मपाल सत्यपाल

आपके 'सफ़ारी' की
चाभी खो जाए,
तो बस भगवान बचाए.

हर सफ़ारी का बीच वाला ताला ६ लीवर का वॉल्ट-ताला होता है.

दूसरे सूटकेसों में ४-लीवर या ५ लीवर के मामूली ताले लगाये जाते हैं और ऐसे तालों को खोलना सफ़ारी के मुकाबले १० गुना आसान होता है.

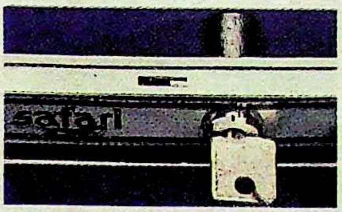

सिर्फ़ इतना ही नहीं, सफ़ारी में ताले के अंदर की "लॉकिंग स्लाइड" ठोस स्टील के एक चैनल में बिठाई गयी होती है. इसीलिए तो ताला तोड़नेवालों की दाल नहीं गलती.

इसी तरह आप देखेंगे कि आपके सफ़ारी की हर चीज़ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है. चेन गार्ड की ही बात लीजिए.

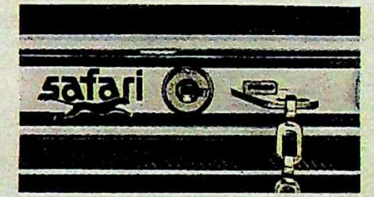

हमने इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया है कि इसमें चेन जोड़ने के लिए, आपको चाभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

या फ़िर देखिए 'गैलेक्सी 2001' सीरीज़ के हमारे सूटकेस. 'ट्विन राइट-साइड-अप' की खास तकनीक की वजह से ये सूटकेस तभी खुल पाते हैं जब उन्हें सीधा रखा गया हो. सूटकेस खड़ा रखा हो और कोई उसे खोलने की कितनी ही कोशिश करे, तब भी वह खुलनेवाला नहीं.

ऊंची क्वालिटी बनाये रखने के लिए हम हमेशा से सूटकेसों की सबसे कड़ी जांच करते आये हैं. इसीलिए तो, आप तक पहुंचने से पहले हर सूटकेस की ९० अलग-अलग बातों के लिए जांच कर ली गयी है, इस बात की हमें तसल्ली रहती है.

जहां तक तालों की बात है, अपना एक छोटा-सा राज़ आपको बता ही दें.

अगर कभी गलती से आपके सफ़ारी की चाभी खो ही जाए तो आप उसे लेकर सीधे अपने शहर के सफ़ारी ऑफ़िस में चले आइए.

वहां आपको मिलेगा एक मैकेनिक जिसे फैक्टरी में हमने पूरे दो हफ़्ते यह सिखाया है कि ऐसे में सफ़ारी के ताले कैसे खोले जाएं.

safari

भरी हैं इसमें सैंकड़ों खूबियां.

Enterprise/SI/05 Hn

साक्षात्कार/पार्वती खान

यदि वे (दूरदर्शन) मेरे गाने रिकार्ड नहीं करते, तो सांप्रदायिकता के पक्षधर हैं

'जिमी-जिमी...आजा...आजा' के रिकार्ड से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली पार्वती खान को दूरदर्शन के धारावाहिक 'नयी दिशाएं' ने घर-घर में परिचित तो करा दिया, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़े 'खान' के कारण उनको धारावाहिक ने विवादास्पद भी बना दिया है। वेस्टइंडीज के छोटे से द्वीप ट्रिनीडाड में जन्मी पार्वती महाराज (अब खान) मूलतः हिंदुस्तानी हैं। अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ी और हिंदी न जानने के बावजूद पार्वती, हिंदी गानों के द्वारा पाश्चात्य देशों में धूम मचा चुकी हैं। ६ वर्ष की छोटी-सी उम्र से ही ट्रिनीडाड टीवी की बाल कलाकार व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रहने व न्यूयार्क, पेरिस (फ्रांस), लंदन आदि शहरों में सफलता अर्जित करने के बाद पार्वती डा० राही मासूम रजा के सुपुत्र नदीम खान से विवाह कर भारत में बस गयीं। जब से उनके नाम को लेकर 'दूरदर्शन' ने आपत्ति प्रकट की है, तब से वह विशेष चर्चा में हैं। प्रस्तुत है, माया' से पार्वती खान (महाराज) की लंबी और बेबाक बातचीत :

माया : गाने की शुरुआत कैसे हुई? गायन कला आपको विरासत में मिली या फिर आपने शौकिया सीखा इसे?

पार्वती : जब मैं ६-७ वर्ष की थी, तभी से मैंने गाना प्रारंभ किया। हां, पहले शौकिया शुरू किया था, पर अब शौक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया है। मैंने ११ वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती थी, उसके बाद मैं न्यूयार्क गयी और तब से लगातार गा रही हूं।

माया : संगीत के साथ-साथ आपने पढ़ाई-लिखाई या प्रशिक्षण प्राप्त करने का सिलसिला जारी रखा या सिर्फ गायन में ही व्यस्त रहीं?

पार्वती : न्यूयार्क से आकर ट्रिनीडाड में मैंने एचएससी (हायर सेकेंडरी) की परीक्षा दी। फिर मैं वापस न्यूयार्क चली गयी। वहां जाकर मैंने छह महीने का 'जेरियोटिक' पाठ्यक्रम पूरा किया, जो कि खास तौर पर प्रौढ़ लोगों के लिए होता है, उसके बाद मैंने 'रेडियो-कार्डियोलाजी' का पाठ्यक्रम पूरा किया। उस समय मेरी उम्र कम थी, अतः इस पाठ्यक्रम के लिए वे मुझे लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैं लंदन चली गयी, वहां जाकर मैंने नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया।

माया : नदीम खान से आपकी मुलाकात कैसे हुई?

पार्वती : जब मैं नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, तब नदीम खान लंदन में फिल्म 'एक बार फिर' के बतौर डायरेक्टर-फोटोग्राफर की हैसियत से आये थे। वहीं एक प्रोग्राम में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी जो कि प्रेम में परिवर्तित हो गयी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैंने उनसे विवाह कर लिया।

माया : बंबइया फिल्मों में आपका प्रवेश गायन से ही हुआ, आपने अब तक किस-किसके गाया?

पार्वती : मैंने अपने रिकार्ड 'जिमी-जिमी में भप्पी लहरी के साथ गाया। उसके बाद फिल्म 'मां कसम', 'अब मेरी बारी', 'श लिए गाया। उषा खन्ना की 'सात बिज 'अंधेरे-उजाले', खैयाम साहब की 'पर्वत के पार', सपन जगमोहन व अजीत वर्मन की 'मशाल' आदि में भी गाने गाये हैं।

माया : आपने मार्डलिंग भी तो किया था?

पार्वती : हां, मैंने माडलिंग बहुत सारी ची के लिए की है—वीआईपी लगेज, बांबे डा ओसीएम, लक्मे टेलकम पाउडर, मोदी का आदि।

माया : 'नयी दिशाएं' में कैसे आयीं आप?

पार्वती : जब सीरियल 'नयी दिशाएं' के लि नदीम फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उस समय निर्माता विवेक वासवानी व निर्देशक इरफान हमारे घर आये। इरफान मुझे अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लगा कि मैं उस पात्र के में सही रहूंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे रोल लेने को कहा। मैंने भी 'हां' कर दिया। अभिनेत्री के रूप में यह मेरी पहली प्रस्तुति थी।

माया : मंडी हाउस से जो विवादास्पद पत्र आया था, उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?

पार्वती : पत्र मेरे पास नहीं आया था, पत्र सीरियल के निर्माता विवेक वासवानी के आया था। जब उन्होंने मुझे बतलाया, तो पहली प्रतिक्रिया थी—मेरी एक जोरदार क्योंकि यह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। मुझे एकबारगी यकीन ही नहीं हुआ था कि कोई इस प्रकार की बात कर भी सकता है। लेकि जब विवेक ने विश्वास दिलाया कि यह दूरदर्शन की ओर से आया है। तब मुझे लगा कि, वाकई यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि सरकारी एजेंसी की ओर से आया था। को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा इंगित करता, तो मैं जवाब दे सकती थी, क्योंकि इस प्रकार हरकतें जातीय तौर पर होती रहती हैं। उन दिनों यहां नहीं थे, वह कश्मीर में फिल्म की शूटिंग करने गये थे। मैं अपने डा० मासूम रजा के पास गयी, उन्हें सा किस्सा बतलाया, तो वह नाराज होते हु बोले, 'क्या बेहूदा बात कर रही हो, ऐसा ही नहीं सकता। तुम कैसे इस प्रकार की कह रही हो। मैंने कहा, "मैं आपको सच बतला रही हूं। विवेक वासवानी ने मुझे बतलाया है कि उनके पास दूरदर्शन से पत्र आया है।" तो वह बोले, "मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई सरकारी एजेंसी लिख सकती है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो यह गंभीर मामला है। वह पत्र लाओ। बिना पत्र देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता

कोई कदम उठा सकता।" लेकिन विवेक ने देने से मना कर दिया।

मायाः फिर क्या हुआ?

पार्वतीः विवेक का उन दिनों दूरदर्शन पर कार्यक्रम चल रहा था, अतः उन्होंने पत्र देने से मना कर दिया। आखिर उन्हें अपने कार्यक्रम की चिंता थी। नदीम को मैंने सारी परिस्थिति लिखी। वह जब वापस आये, तो उन्होंने विवेक पर पत्र की प्रति देने के लिए दबाव डाला। पत्र मिलने पर उसे लेकर मैं डा० रजा साहब के पास गयी। पत्र देखकर उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री व दूरदर्शन निदेशक से पूछा जाये कि ऐसा क्यों हुआ? और उन्होंने पत्र लिखा भी और जवाब के लिए दो महीने का समय दिया। यदि दो महीने में हमें जवाब नहीं मिला, तो हम प्रेस में जायेंगे। हम इंतजार करते रहे, परंतु दो महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया।

मायाः तो क्या आप प्रेस में गयीं?

पार्वतीः जी हां, यदि वे जवाब दे देते और अपनी गलती स्वीकार कर लेते, तो मामला रफा-दफा हो जाता। लेकिन उनकी ओर से एक भी शब्द लिखकर नहीं आया। फिर राही साहब ने बंबई के एक दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखा और उसके प्रकाशित होने पर तो यह बात आग की तरह फैल गयी। फिर दूरदर्शन वाले बोले कि हमने विवेक वासवानी को इस पत्र के संदर्भ में उत्तर लिखा था। परंतु शिकायत तो हमने की थी, विवेक ने नहीं।

मायाः कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि यह सब राही साहब का 'पब्लिसिटी स्टंट' था?

पार्वतीः जब और कुछ नहीं कह सकते, तो यही कह दिया कि यह 'पब्लिसिटी स्टंट' है।

मायाः विवेक वासवानी की इस पूरे पत्र-प्रकरण में क्या भूमिका रही? आप इसे क्या मानती हैं?

पार्वतीः विवेक ने यह बहुत गलत किया। वह बहुत ही 'पब्लिसिटी माइंडेड' हैं। अंत में उनका प्रोग्राम भी अच्छा नहीं रह गया था। वैसे भी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को लोग जल्दी भूल जाते हैं।

मायाः अब आपके प्रति दूरदर्शन और रेडियो का क्या रवैया है?

पार्वतीः एक गायिका के रूप में वे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। हर गायिका या कलाकार की इच्छा होती है कि वह टीवी पर अपना प्रोग्राम पेश करे। मैंने दूरदर्शन से संपर्क स्थापित किया, तो उन्होंने मना कर दिया, कि अभी इंतजार कीजिये। लेकिन क्यों? यह पता नहीं। यदि वे मेरे गाने रिकार्ड नहीं करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वे सांप्रदायिकता के पक्षधर हैं।

—अक्षरा

साक्षात्कार/डा० राही मासूम रजा

नाम पर किसी मजहब का कापीराइट नहीं होता

लगभग डेढ़ दशक पूर्व अपने उपन्यास 'आधा गांव' से समूचे रचना संसार को अचंभित कर देनेवाले डा० राही मासूम रजा फिल्म जगत में बुद्धिजीवी कथा-पटकथा एवं संवाद-लेखकों में गिने जाते हैं जिन्होंने दर्जनों सुरुचिपूर्ण तथा बाक्स आफिस पर सफल फिल्में लिखी हैं। एक बेबाक शख्सीयत के रूप में जब वह किसी हस्ती के बारे में बोलते या लिखते हैं, तो प्याज के छिलकों की तरह परत-दर-परत उसके विभिन्न पहलुओं को उभारकर रख देते हैं। वह न दक्षिण पंथी हैं और न ही वामपंथी— वह अपने को मानवतावादी मानते हैं। उनके घर में मंदिर भी है, गिरजाघर भी और कुरान पाक की पाकीजगी भी। इसलिए जब दूरदर्शन के एक अधिकारी ने उनकी पुत्रवधू पार्वती खान के नाम के बारे में एक पत्र लिखा, तो उनका मानवतावादी गुस्सा फूट पड़ा, फलतः उनकी जिस पुत्रवधू के बारे में उनके आस-पड़ोस के लोग भी नहीं जानते थे, वह रातोरात सुर्खियों का विषय बन गयी। कैसे? इस संदर्भ में प्रस्तुत हैं, 'माया' से हुई उनकी बातचीत के अंशः

मायाः *आपकी पुत्रवधू पार्वती खान के नाम को लेकर दूरदर्शन का जो विवादास्पद रुख रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है?*

राहीः मैं तो यही कह सकता हूं कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 'पार्वती' नाम पर हिंदुओं का अधिकार तो नहीं है। बहुत से मुसलमान घरानों में हिंदू नाम व हिंदू घरानों में मुसलमान नाम रखे जाते हैं। किसी भी नाम पर किसी मजहब का कापीराइट तो नहीं होता। मेरी बहू ने हिंदू होते हुए मेरे लड़के से शादी की है, तो यह तो तारीफ की बात है। मैं चाहता, तो उसे आयशा या सुल्ताना भी बना सकता था, जैसा कि नवाब पटौदी ने किया, परंतु मैंने उसे पार्वती ही रहने दिया। अगर कोई आदमी इस पर एतराज करता है, तो इसे उसका पागलपन करार देकर, उसे माफ किया जा सकता है। लेकिन ऐसी सरकार, जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, उसी का कोई इंस्टीट्यूट अगर हमसे यह कहे कि आप फलां नाम हटा दीजिए, इससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई किसी मधुमालती (कार्यक्रम नियंत्रक) से नहीं है। उस बिचारी को तो मैं जानता भी नहीं, मेरी लड़ाई दूरदर्शन से भी नहीं है। मेरी लड़ाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से है। मैंने एक सवाल उठाया था, 'ऐसा क्यों हुआ?' उसका उन्हें जवाब देना चाहिए था।

मायाः *इसीलिए आपने एक दैनिक में पत्र लिखा? उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई?*

राहीः बड़े कमाल की प्रतिक्रिया हुई। मैं कतई आशा भी नहीं करता था कि लोग इतने बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को लेंगे। मेरे पास हिंदुस्तान के हर हिस्से से पत्र आये कि यह बड़ी बेहूदा बात है। हम आपके साथ हैं। ४००-५०० लोगों ने तो राष्ट्रपति के पास पत्र भी लिखे, जिनकी प्रतियां मेरे पास भेजी हैं। इन सबको देखकर मुझे लगा कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता के लिए वाकई जगह है।

मायाः *आप काफी 'प्रोग्रेसिव' विचारों के माने जाते हैं। क्या जरूरी था कि पार्वती महाराज अपने नाम के आगे 'खान' ही लगायें?*

राहीः मैंने तो पार्वती से नहीं कहा कि तुम पार्वती खान लिखो। कभी वह अपने मायके का नाम 'पार्वती महाराज' लिखती है, तो कभी केवल पार्वती। मैंने तो उससे यह कभी नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है? उसकी जो मर्जी आये, वह लिखे। यह बात तो हमारी सरकार की एक संस्था की है कि तुम पार्वती के आगे 'खान' नहीं लिख सकतीं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पार्वती महाराज है तब भी मेरी बहू है, खान है तब भी और केवल पार्वती है तब भी। हां, मैं उसको आयशा (शर्मिला ठाकुर का विवाह के बाद बदला नाम) नहीं होने दूंगा। मैं धर्म-परिवर्तन नहीं होने दूंगा। वहां मेरा विरोध होगा। पार्वती का नाम पार्वती ही रहेगा। आगे वह जो चाहे लगाये, उसमें दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है। अपने को वह कैसे पहचनवाना चाहती है, वह उसकी मर्जी है। मेरे घर में और भी दो बहुएं हैं, वे भी हिंदू हैं। दोनों में से किसी का भी हमने नाम या धर्म परिवर्तन नहीं किया। मेरे खयाल से पार्वती ने अपने घर में छोटा-सा मंदिर बना रखा है, जहां वह पूजा भी करती है। वह तो खैर मेरी बहू है, मेरे घर में दो नौकर हिंदू हैं, उनका मंदिर है, एक ईसाई है, उसका चर्च है। हां, मेरे घर में मस्जिद नहीं मिलेगी आपको। जो आदमी मेरे घर में काम करता है, उसको अपने धर्म को मानने का पूरा हक है। सब खुश रहें, मैं तो बस यही चाहूंगा और मुझे क्या मतलब!

—अक्षरा

झीनी-झीनी बीनी चदरिया

सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' की जहां एक ओर हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी तथा अमरकांत जैसे ख्यातनामा साहित्यकार सराहना कर रहे हैं, वहीं 'आवाजे मुल्क' जैसे अखबार उसको धिक्कार रहे हैं। बनारस, जो उपन्यास का कैनवास है और जहां लेखक ने दस वर्षों तक रहकर नेशनल इंटर कालेज, पीलीकोठी में अध्यापन कार्य किया तथा अपने उपन्यास की सामग्री जुटायी, उसी बनारस में उसका सर्वाधिक विरोध हो रहा है। विरोध के कारण बताये जा रहे हैं, उपन्यास में आये वे अंश जिनको इस्लाम-विरोधी करार दिया जा रहा है। सोच और सरोकार के नजरिये से देखने वाले आलोचक इस उपन्यास को बिस्मिल्लाह की प्रगतिशीलता का एक और सबूत मान रहे हैं। उसी का सुफल है कि उन्हें हाल ही १९८६ का केडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है।

कथानक : यों 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' की पूरी कथा दो ध्रुवों—शोषक और शोषित—की कथा है, जो ताना व बाना खंड तथा क्षेपक के अंतर्गत विशाल फलक पर फैली हुई है। सरमायेदारों में एक तरफ हैं, अलईपुर के गिरस हाजी मतीउल्ला, हाजी अमीरुल्ला, हाजी मिनिस्टर तथा हबीबुल्ला (जो बाद में स्वयं हाजी हो जाते हैं) तथा दूसरी तरफ मजलूमों में मतीन-अलीमुन दंपति, बुजुर्ग रऊफ चचा, लतीफ, बशीर, अल्ताफ, नजबुनिया, नसीबुन बुआ, रेहाना, कमरुन जैसे टूटते-बिखरते लोग। इसी प्रकार दूसरी पीढ़ी में सियासी और शोषण की राजनीति के नये अंकुर हैं, शरफुद्दीन एमएलए तथा दूसरी तरफ उनसे लड़ता और जद्दोजहद करता मतीन का लड़का मजदूरों का हमदर्द इकबाल अंसारी।

उपन्यास का मूलबिंदु है 'कोआपरेटिव सोसायटी' का गठन, क्योंकि मतीन को शहर उत्तरी के एमएलए अल्ताफुर्रहमान अंसारी से पता चल गया है कि सरकार ने बुनकरों को काफी सहूलियतें दे रखी हैं। वे रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लोन ले सकते हैं तथा अपना माल सीधे सरकार को तथा बाहर के मुल्कों को निर्यात कर सकते हैं। इसी फिराक में मतीन रऊफ चाचा के साथ बानी बिनने वाले कारीगरों को जुटाने, उनसे पैसा इकट्ठा करने और बैंक से संपर्क करने में लगा रहता है तब तक हाजी अमीरुल्ला की चेयरमैनशिप में एक फरजी कोआपरेटिव सोसायटी बन जाती है जिसमें मतीन, लतीफ, अल्ताफ, रऊफ, बशीर वगैरह के फरजी दस्तखत होते हैं। हाजी अमीरुल्ला को सरकार से सत्तर हजार रुपए मिलते हैं जिससे वह पावरलूम्स बैठाते हैं। लतीफ-वतीफ थोड़ी चूं-चपड़ करते हैं, लेकिन शरफुद्दीन की बनरभभकी से वे खामोश हो जाते हैं। जहां इस कोआपरेटिव के चलते हाजी अमीरुल्ला की साड़ियां विदेशों में निर्यात होने लगती हैं, वहीं मजदूर बेकार होने लगते हैं। अंत में मतीन हारकर मऊनाथ भंजन चला जाता है। जैसे बनारस के गिरस्ता एवं कोठीवाले अपने शोषण का जाल फैलाये हुए हैं, वैसे ही मऊनाथ भंजन में भी बिचौलियों की कमी नहीं है। सरकार द्वारा जो भी सहायता मिलती है, उसे बिचौलिये ही हड़प कर जाते हैं। मतीन मऊनाथ भंजन की स्थिति देखकर और भी विचलित हो जाता है और अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मऊ से अच्छा तो बनारस ही था। वह सोचता है कि गरीब तो हर जगह एक ही जैसा होता है और वह मऊनाथ भंजन छोड़ देता है।

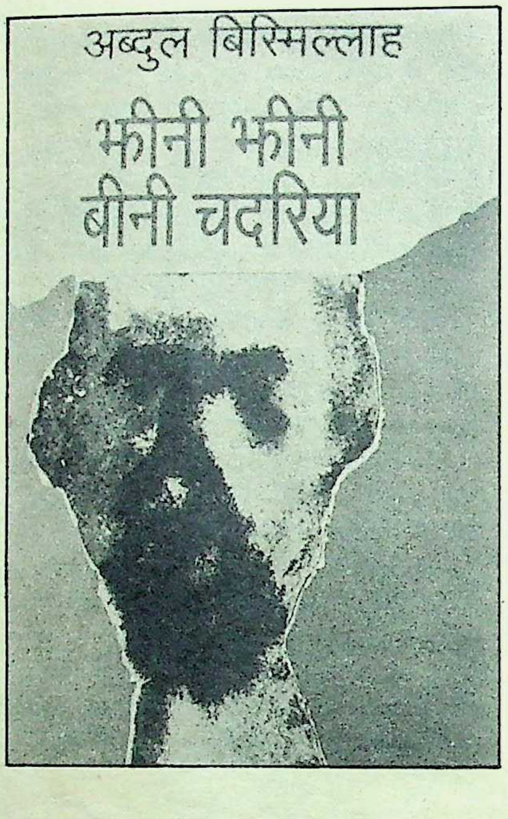

यद्यपि कथानक बहुत सीमित-सा नजर आता है, लेकिन इसी कथा-सूत्र के बहाने उपन्यासकार बनारस जिले के ७५ हजार करघों पर काम करनेवाले दो लाख बुनकरों की जाती जिंदगी, उनके रहन-सहन, उनके शोषण, उनके रीति-रिवाज, उनकी कुरीतियों और अंधविश्वासों का ताना-बाना बुनता है। बनारसी साड़ी बिनने वाले मजदूरों की जो दुर्दशा है, उनके शोषण का जो भयानक चक्र बड़े गिरस्तों और गोलघर के कोठीवालों के बीच फैला हुआ है, उपन्यासकार उसी कुचक्र का परदाफाश करता है। वह बताना चाहता है कि जो क रात-दिन एक करके बजबजाती नालियों और की बदबूदार कोठरियों में टीबी से आक्रांत प साथ साड़ियों को तैयार करने में लगा है, जिंदगी की असलियत क्या है? उसकी बेचकर गिरस्त दिनोदिन मोटा होता जा कोठियों पर कोठियां बनती जाती हैं, क्या भर भोजन, पीने का पानी तथा सांस लेने हवा भी नसीब हो पाती है?

विवादास्पद अंश : जहां तक विवा अंशों का प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि उपन्या ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है जो आस्थाओं के विरुद्ध जान पड़ते हैं और उन ठेस पहुंच सकती है, "... हिंदुस्तान के मुसलमा इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने की धरती में ढेरों शहीद खोज निकाले हैं जो हर बृहस्पतिवार के रोज अपनी शक्ति का प जनता को दिया करते हैं। उनमें एक चंदन शहीद हैं।" इस्लाम में शराब की मुमानियत तथा तस् की मुमानियत पर उपन्यासकार की दृष्टि पड़े नहीं रही है, "... हालांकि इस्लाम में शराब की मुमानियत है, पर शायरों के लिए ह्विस्की इंतजाम कर लिया गया है। भई मजबूरी है। इस्लाम में तो तस्वीर की भी मुमानियत है बुरचोदी के ऐसा सरकारी कानून है कि जिंद आदमी भले इस गुनाह से बच जाये, मगर ह लिए जाते वक्त तो फोटो खिंचाना जरूरी है जाता है, वरना पासपोर्ट ही नहीं बनेगा।"

शोषण द्वारा किये गये पाप को पु बदलने के लिए हबीबुल्ला हज के लिए ज लेकिन अपनी आदतों से वह बाज नहीं आते चलते वक्त बीवी ने दो लेडिस घड़ियों के लि रखा था, बिटिया ने टेपरिकार्डर मंगवाया साहबजादे ने सीको-५ जापानी घड़ी और एक के लिए आखिरी दम तक ताकीद की थी, भला छोड़ देते? फिर एम्मन कउन गुनाह है, वास्ते ला रहे हैं, कउनों तस्करी-फस्करी थों रहे हैं कि बुरचोदी के अल्लामियां के बुरा ल

हाजी मिनिस्टर का चरित्रांकन काबिलेगौर है। एक जगह हाजी मिनिस्टर के उपन्यासकार लिखता है, "हाजी मिनिस्टर के पास खड़े-खड़े देर तक पड़वे की बोटी च और कुएं के चबूतरे पर नहाती हुई मल्ला देखते रहे।"

उपन्यासकार ने मुसलमानों में अंधविश्वासों को भी उजागर किया है। मुस में विशेषकर निचले तबकों में भूत-प्रेत, जिन्नात, टोना-टमाना जैसी बातों का बड़ा चाहे गाजी मिया हों या मखदूम शाह— मजारों पर हर बृहस्पति को मेला लगता है, उर्स लगा करते हैं और वहां पर इस प्रकार औरतें जाकर खेलती-हबुवाती हैं। इस उप बशीर की लडकी रेहाना के ऊपर कोई शै उतरवाने के लिए वह मखदूम शाह की म जाती है।

स्त्रियों की दशा : मुसलमानों में स्त्रियों की दशा है, उसका भी बड़ा ही यथातथ्य वर्णन न्यासकार ने किया है, "औरत जात की आखिर सियत ही क्या है? जब चाहो चूतड़ पर लात रकर निकाल दो। औरत का इस्तेमाल ही क्या ? कतान फेरे, हांडी-चूली करे, साथ में सोये, बच्चे ने और पाव दबाये। इनमें से अगर किसी भी काम हीलाहवाली करे तो कानून-इस्लाम का पालन रो और बोल दो कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। लाक! तलाक! तलाक! बिरादरी में तो 'महर' का भी झंझट नहीं है।"

मुस्लिम स्त्रियों से संबंधित मसलों में शादी-विवाह और तलाक के मसले सबसे अहम हैं। सीलिए उपन्यासकार ने शरीअत का सवाल उठाया है, "इस शरीअत में भी बड़ा झंझट है। ये भी कोई बात हुई कि अपनी ही बीवी को आप दुबारा सिर्फ इसलिए नहीं रख सकते कि आपने तीन बार उसके सामने 'तलाक' लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया है।"

आर्थिक रूप से टूटे हुए मेहनतकश मजदूर की मजबूरी कुछ इतनी बड़ी होती है कि वह अपनी जवान लड़की की शादी के लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ़ पाता। फूल जैसी लडकी की शादी पांच बच्चों के बाप से करनी पड़ती है। बशीर भी इसी बात का शिकार है, उसे रेहाना की शादी एक अधेड़ से करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ है लतीफ जोकि शरीअत को धता बताकर कमरून को पुनः बिना हलाला के रख लेता है। दरअसल लतीफ नशे में धुत होकर अपनी पत्नी कमरुन को तलाक देता है, लेकिन जब वह होश में आता है, तो उसे जबरदस्ती अपने घर में रख लेता है, लेकिन उसका पुनः उसी घर में बिना हलाला के आना रस्मो-रिवाज को चुनौती देना था, "दुनिया में क्या ऐसा भी कहीं हुआ है कि तलाकशुदा मुसलमान औरत बगैर 'हलाला' के फिर अपने शौहर के साथ आकर रहने लगे? मजहब के साथ इतना बड़ा खिलवाड़! इतना बड़ा गुनाह! अगर आज वह अलग न रहकर अपने मां-बाप के साथ रहती होती, तो क्या ऐसा हो सकता था? काटकर फेंक दी जाती वह। उसने पूरी बिरादरी की नाक कटा दी है।" इसके लिए पंचायत बैठती है। पंच बड़े नाराज हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता कि नशे में दिया हुआ तलाक तलाक नहीं माना जायेगा। रऊफ चाचा ने कहा, "जब तिलाक भोवै हीं तब फिर हलाला कइसा? लतीफ त नसे की लत में ही तिलाक दिए रहेन। कमरुन से पूछ ।" फिर आगे कहते हैं, "आप लोग आपन-आपन छोड़ौ। लतीफ को अब होस आ गोवा है त ओके से रहे देव। ओके अपने किये की सजा मिल । इस्लाम सौहर-बीवी के अलग करे के नाहीं ।" फिर रऊफ चाचा की बातों का समर्थन हुए मतीन कहता है, "चच्चा की बात एद्दम है। इ पंचायत-संचायत खतम करौ। हमरी रादरी में एक जने इ हिम्मत कियेन, इ तारीफ की है। आगे से इ देखा जाय कि कोई अपनी बीवी एतरके तिलाक न देय।"

साक्षात्कार/अब्दुल बिस्मिल्लाह

मजहब को नहीं, सड़ी-गली रूढ़ियों को बेनकाब किया गया है

हिंदी कथा जगत को नया अनुभव बोध कराने वाले और बुनकरों की जिंदगी का बहुरंगा ताना-बाना बुनने वाले ३६ वर्षीय अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी कृति 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' के कारण चर्चित-बहुप्रशंसित ही नहीं हुए, सांप्रदायिक तत्वों की नजर में विवादग्रस्त हो इस्लाम विरोधी भी करार दिये गये हैं। उनके उपन्यास और उसके खिलाफ उभरे उग्र विरोध पर 'माया' ने उनसे बातें कीं। प्रस्तुत हैं, प्रमुख अंश :

माया : आपके उपन्यास का सहसा विरोध क्यों?

बिस्मिल्लाह : यह मेरे लिए भी एक सवाल है। कारण मेरा यह उपन्यास १९८६ में छपा था। इस बीच वह पाकेट बुक के रूप में भी आ चुका है और दूसरा संस्करण भी छप चुका है। १९८७ में उस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और इस वर्ष अ०भा० केडिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लगभग सवा दो साल तक तो उसको लेकर कोई विवाद-विरोध नहीं हुआ। लगता है उपन्यास पुरस्कृत और लोकप्रिय होने से सहसा निहित स्वार्थों की आंख की किरकिरी बन गया है।

माया : कैसे निहित स्वार्थ?

बिस्मिल्लाह : बुनकरों के शोषक कोठीवाले जो अपने स्वार्थों की रक्षा में ही मजहब और समाज की रक्षा समझते हैं।

माया : विरोध का मूल मुद्दा क्या है?

बिस्मिल्लाह : विरोध के मूल में जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं, वे मजहबी हैं जिसमें सांप्रदायिकता का जहर है। उपन्यास के वस्तुपक्ष अथवा कलापक्ष पर विरोध होता, तो बात चिंता की नहीं थी। मेरा मानना है कि इस उपन्यास का धर्म संप्रदाय या व्यक्ति के नजरिये से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उपन्यास में मुस्लिम रीति-रिवाजों, त्यौहारों का जो ब्यौरा है, उसे चंद लोग इस्लाम का विरोध करार दे रहे हैं। यह सरासर गलत है। 'आवाजे मुल्क' के लेख में यह आरोप भी है कि 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' में वाराणसी के बुनकरों का मजाक उड़ाया गया है। भला कोई लेखक अपने पात्रों का मजाक कैसे उड़ायेगा। चाहे वह खल पात्र ही क्यों न हो? लेखक का उससे रागात्मक संबंध होता है। फिर मैं दस वर्षों तक उन्हीं बुनकरों के बीच रहा और उनके दुख-सुख का साझीदार बना हूं।

माया : यह भी आरोप है कि उपन्यास में मुस्लिम धर्म, संस्कृति और जिंदगी के अंधेरे पक्षों को ही उजागर किया गया है।

बिस्मिल्लाह : उपन्यास में मजहब को नहीं, सड़े-गले रिवाजों-रूढ़ियों को बेनकाब किया गया है। उपन्यास में मुस्लिम संस्कृति है, यह भी एक अधूरा सच है। दरअसल इसमें श्रमिक संस्कृति है। संयोग से इस पेशे में मुसलमान अधिक हैं। साथ ही जिंदगी के अंधेरे पक्ष को नहीं व्यवस्था के क्रूर, जालिम और लुटेरे चरित्र को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, मैंने।

माया : इस उपन्यास में जगह-जगह गंदी-भद्दी गालियों का प्रयोग आपने किया है, यह भी कहा जा रहा है।

बिस्मिल्लाह : उपन्यास में गाली का प्रयोग है, ऐसा उन लोगों को दिखायी पड़ता है जो शब्दों को गाली मानते हैं। गाली नीयत में होती है। ये पात्रों की जिंदगी की भाषा के शब्द हैं। जीवन में ऐसे प्रयोग पर आपत्ति नहीं, तो रचना में यह दुराग्रह क्यों?

माया : सुना है आपके इस उपन्यास पर सीरियल, फिल्म बनाने के प्रस्ताव आ रहे हैं।

बिस्मिल्लाह : ऐसे कुछ प्रस्ताव आये जरूर हैं, जिन पर मैं विचार कर रहा हूं। किंतु सवाल है कि उपन्यास का जब इतना विरोध है, तो फिर इस पर सीरियल व फिल्म बनने पर क्या हश्र होगा?

माया : यह भी कहा जाता है कि लेखक ने बुनकरों को पार्टी का झंडा देकर और संगठित करने का नारा देकर उपन्यास को नारेबाजी में बदल दिया है।

बिस्मिल्लाह : उपन्यास में मैंने शोषण के शिकार दीनहीन, वंचित, विपन्न बुनकरों के नारकीय जीवन का लेखा-जोखा पेश किया है। क्या शोषण के खिलाफ विरोध, जागरण और संगठन की स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया-परिणति को दर्शाना नारेबाजी कहलायेगा। उपन्यास में ऐसे लोगों की कथा है जो टूटते हुए भी साबुत हैं, यथास्थिति से समझौता नहीं करते। उससे लोहा लेना और बदलना चाहते हैं। इसके अलावा बुनकर समुदाय के शोषण में मददगार उसकी अपनी रूढ़ परंपराएं, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक कठमुल्लापन और सांप्रदायिक सोच है। क्या यह सब उजागर करना नारेबाजी है?

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

यों तो चरित्रों के चयन और उनके विन्यास में उपन्यासकार ने अत्यंत सूझबूझ बरती है, लेकिन मतीन-अलीमुन तथा इकबाल का चरित्र अद्भुत बन पड़ा है। पूरे उपन्यास में मतीन और अलीमुन केंद्रीय पात्र हैं जो एक परिवार न होकर बुनकरों की बदहाली, आर्थिक तंगी तथा शोषण के प्रतीक हैं। जहां मतीन को पूरे उपन्यास में टूटते-बिखरते-जद्दोजहद करते हुए दिखाया गया है, वहीं मतीन की पत्नी हर पल उसके संघर्ष में साथ देती है। उसकी भावुकता की अंतिम परिणति तब देखने को मिलती है, जब वह मतीन से कहती है, "बुरा न मानेवं। हम ठीक कहीला। हमरा कउन ठिकाना, नजबुनिया तुहें बहुत चाहेती, तू इससे बियाह कर लेव। हम्मैं कउनो एतराज नहिने। हम खुद चच्ची से कहि देब। नजबुनियौ से। हमरा त अब चल-चलाव है।" कहना न होगा कि वह अपने पति के लिए अपनी भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखती। वह यह भी जानती है कि मतीन नजबुनिया को चाहता है। अजब समर्पण का भाव है।

चरित्रों में सर्वाधिक प्रगतिशील और बेबाक चरित्र है, इकबाल का। यह नयी क्रांति का द्योतक है। वह सरमायेदारों के खिलाफ तो आवाज बुलंद करता ही है, कर्मकांडों के भी खिलाफ है। अलीमुन के मरने के बाद जब उसकी विमाता नजबुनिया उससे सिपारा पढ़कर मां को बख्शने के लिए कहती है, तो वह साफ इनकार कर देता है। नजबुनिया जब उस पर बिगड़ती है, तो वह ढिठाई से कहता है, "यह सब ढोंग है। मरनेवाला मर गया। अब उसके लिए कोई एक कुरआन नहीं, दस कुरआन पढ़ के उससे क्या होने वाला है? यह सब सरमायादारों का बनाया हुआ ढकोसला है। खाने-पीने का धंधा है। हमें जो करना चाहिए, उसकी ओर तो हम गौर नहीं करते, उलटे तरह-तरह के फालतू कामों में फंसे रहते हैं।"

उपन्यास की भाषा अत्यंत सहज एवं बनारस की बुनकर संस्कृति-सभ्यता के अनुरूप है। संवाद भी बड़े सटीक हैं, लेकिन गालियों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि बड़ा अटपटा-सा लगता है। लेकिन उपन्यासकार उन्हें गाली न मानकर पात्रों की जिंदगी की भाषा मानता है। उपन्यास की शैली ऐसी है कि रिपोर्ट की तरह परत-दर-परत घटनाएं खुलती जाती हैं।

उपन्यासकार रेहनवा के वर्णन में कुछ ज्यादा ही रस लेता नजर आता है, "नीले साटन की पेरानी में उसकी छोटी-छोटी छातियां कुछ ज्यादा ही उभरी हुई दिख रही थीं।" नजबुनिया के प्रसंग में तो उपन्यासकार अति यथार्थवादी हो गया है, "पांच दिन तक नापाक बनी रही। यह महीना-वहीना का झंझट भी बहुत बुरा है।...वह अचानक अपनी पेरानी के ऊपर से अपनी छातियों पर हाथ फेरती है और अपना दुपट्टा ठीक करती है।"

कहीं-कहीं उपमाएं बहुत अच्छी बन पड़ी हैं, जैसे मरणासन्न अलीमुन मतीन की बुनी हुई साड़ी को देखकर जो भाव व्यक्त करती है, उसे उपन्यासकार ने अत्यंत खूबी से व्यक्त किया है, "अपने शौहर के श्रम को मानो वह आत्मसात कर लेने की इच्छा से ही उसके एक-एक धागे को इस रही है जैसे वह धागा न होकर उसके पेट कोई मासूम शिशु हो— लाल-लाल, प्या लेकिन कहीं-कहीं उपमाएं बड़ी असंगत प्रतीत हैं, जैसे— "...उसकी धोती अस्त-व्यस्त हो और चित लेटी उस लड़की का एक नन्हा कबूतर के बच्चे की तरह झांक रहा है।" ऐसा है जैसे स्तन भी कोई उड़नेवाली चीज हो।

उपन्यासकार का चाहे विरोध हो या म वह अपने उद्देश्य में सफल रहा है, उसका मा कि वे ही लोग इसके विरोध में हैं, जो निहित में लिप्त हैं। मैंने उपन्यास में मजहब को नहीं गले रीति-रिवाजों और रूढ़ियों को बेनकाब है। उसने बुनकरों की कुरीतियों, उनमें प्र अंधविश्वासों-लोकापवादों का खुलकर वर्णन है। बुनकरों का खून पीने वाले जोकों की भी कड़ी खबर ली है। वैसे तो यह पुस्तक पढ़े बुनकरों तक भी पहुंच जाये, तो यह उम्मीद क है कि वे इसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उनके ऊप जाहिलियत का कम असर नहीं है। नयी शिक्षा की रोशनी वे अपने तक पहुंचने ही नहीं देना चा जो भी हो, कम-से-कम इस उपन्यास का संदेश बुनकरों तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो शोष शिकार हैं, शायद इससे उनमें कुछ जागृति आये वे अपने यथार्थ जीवन में इन शोषकों के प्रति ए हो सकें। समग्रतः कहा जा सकता है कि हिं कथा साहित्य में यह उपन्यास मील का पत्थर

—डा० मुश्ताक

"मेरी"
22 कैरट् स्वर्ण-आवृत जेवरों की चातुरी में है वीश्व नामी उत्तमता की प्रक्रुति। चमकीला सुन्दरी। सब की मन पसन्द, बेजाड़ रंगरूप में गारंटी जेवरों। मंगवाते वक्त जेवरों की संक्षा सूचीत करे। वी.पी.पी. खर्च अलग। मुफत केटलाग के लिए लिखे।

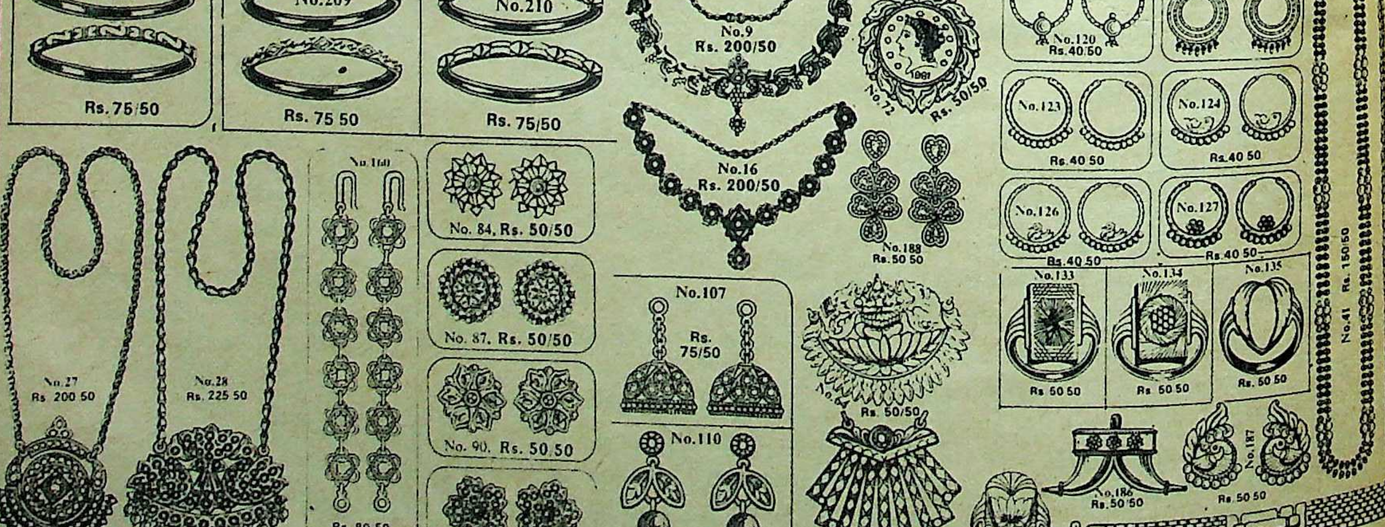
No.214
Rs. 75/50
No.209
Rs. 75 50
No.210
Rs. 75/50
No.9
Rs. 200/50
No.72
Rs. 50/50
1981
No.120
Rs.40/50
No.121
Rs.40/50
No.123
Rs.40 50
No.124
Rs.40 50
No.126
Rs.40 50
No.127
Rs.40 50
No.27
Rs 200 50
No.28
Rs. 225 50
No.160
Rs. 80 50
No. 84, Rs. 50/50
No. 87. Rs. 50/50
No. 90. Rs. 50 50
No.93 Rs. 75 50
No.16
Rs. 200/50
No.188
Rs. 50 50
No.107
Rs. 75/50
No.110
Rs. 40/50
No.64
Rs. 50/50
No.67
Rs. 50/50
No.140
Rs. 50 50
No.133
Rs 50 50
No.134
Rs 50 50
No.135
Rs. 50 50
No.186
Rs. 50 50
No.187
Rs. 50 50
No.193 Rs. 65 50
No.41 Rs. 150/50

MERI GOLD COVERING WORKS
P.O. BOX : 1405, 14, RANGANATHAN STREET
T. NAGAR, MADRAS - 600 017

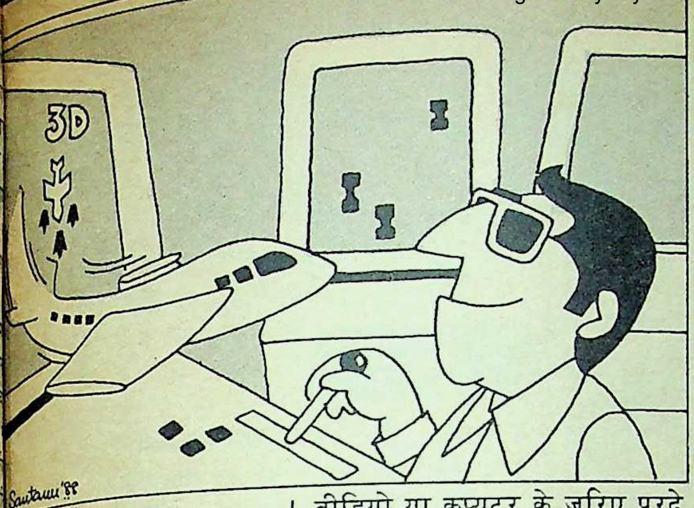

त्रिआयामी वीडियो खेल

इस संसार में किसी वस्तु के कितने आयाम हो सकते हैं? इस सवाल र वैदिक काल से ही अनिर्णीत बहस ारी है, लेकिन पश्चिम के उच्च कनीक विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं क हर वस्तु के अधिकतम दस ायाम हो सकते हैं। बहरहाल, नुष्य केवल तीन आयामों— लंबाई, ौड़ाई और ऊंचाई या गहराई को ही ख-समझकर ग्रहण कर सकता है। फर भी इन तीनों आयामों को टीवी, वीडियो या कम्प्यूटर के जरिए परदे पर उतार देना सरल कार्य नहीं था, लेकिन मनुष्य अपनी कोशिशों से चमत्कार करके दिखाता रहा है। पहले त्रिआयामी फिल्में बनीं, उसके बाद बने त्रिआयामी वीडियो और अब वीडियो गेम निर्माता कंपनियों 'सेगा' और 'निन्तेंदस' ने अत्यंत विकसित त्रिआयामी वीडियो खेलों का निर्माण करने मे सफलता पा ली है।

यह सर्वथा अजूबा त्रिआयामी वीडियो खेल देखने के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुत: मनुष्य जब किसी वस्तु को देखता है, तो उसकी छवि ग्रहण करने में दोनों आंखें एक दूसरे की परस्परपूरक होती हैं। इसी आधार पर त्रिआयामी वीडियो खेल के आविष्कर्ताओं ने दर्शकों के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले (एलसीडी) तकनीक पर आधारित चश्मों का निर्माण किया है और इन्हीं चश्मों के जरिए ही इस त्रिआयामी वीडियो खेल का आनंद लिया जा सकता है। सामान्यत: इस चश्मे को पहन लेने से शीशों पर लगे रसायनों के कारण आपको दोनों आंखों से किसी वस्तु के अलग-अलग रूप नजर आयेंगे, एक आंख से यदि वह स्पष्ट नजर आयेगी, तो दूसरी से धुंधली। लेकिन जब आप यह चश्मा लगाकर त्रिआयामी वीडियो खेल देखेंगे, तो उस समय दृश्य की आवृत्ति इतनी तेज होगी और दोनों आंखों से देखने का तालमेल ऐसा बैठेगा कि आपको एक ही दृश्य नजर आयेगा, जो त्रिआयामी होगा।

इन त्रिआयामी वीडियो खेलों के कैसेट की कीमत ४० डालर है और त्रिआयामी चश्मा ५० डालर में मिल सकता है, जिसे सिर्फ एक ही बार खरीदना होगा।

नयी दूरबीन

'देखना' एक कला है और पक्षियों को देखना कला की एक छटा। दि हमारे पास सलीम अली थे, तो श्चिम के पास डा० विलियम बीचर है। डा० बीचर शिकागो एकेडमी आफ साइंसेज के निदेशक रह चुके हैं। सलीम अली की रुचि केवल पक्षियों में थी और जिस प्रकार की दूरबीन से वह पक्षियों का जायजा करते थे— डा० बीचर की नजर में ह भारी थी। डा० बीचर की तो घने गलों के हर प्राणी में दिलचस्पी रही और उनकी नजर में इस दूरबीन जंगलों में ले जाना असुविधाजनक । इसके साथ ही उन्होंने यह भी सूस किया कि दूरबीन निर्माता नाज़ियो पोर्रो के बाद के इन डेढ़ वर्षों में किसी ने दूरबीनों के कास की जहमत नहीं उठायी।

तीन दशकों तक डा० बीचर नी जेब से करीब पांच लाख डालर करके जंगलों में घूमते रहे। के साथ ही उन्होंने ऐसी दूरबीन के निर्माण में भी सफलता प्राप्त कर ली, जो प्रचलित दूरबीनों से वजन में ८३ से ८८ प्रतिशत तक हलकी है। इसकी एक और आश्चर्यजनक खासियत यह है कि यह सिर्फ डेढ़ इंच लंबी है, जिसे सामान्य चश्मे की तरह पहना जा सकता है। नेत्र-विज्ञान में हुई तरक्की के कारण ही डा० बीचर यह दूरबीन बना सके। उन्होंने पारंपरिक शीशों की जगह बेहद हल्के और एक मिलीमीटर तक पतले शीशों का प्रयोग किया। ये शीशे इस प्रकार बनाये गये हैं, जिनमें प्रकाश का क्षय कम-से-कम होता है। इस नयी दूरबीन से दूर की वस्तु को सहज रूप से देखना अब बेहद सरल हो गया है। खासकर पक्षी और वन्य-प्राणी प्रेमियों के लिए तो यह शुभ संवाद है।

अश्लील कंप्यूटर

कंप्यूटरों के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। त्रिआयामी कंप्यूटरों के बाद अब ऐसे कंप्यूटर भी बाजार में आ गये हैं, जिनके जरिए परदे पर उभरी आकृति आपके आदेश पर आप जैसा चाहेंगे, वैसी हरकत करने लगेगी। इसे कामोत्तेजक कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। इसके जरिये आप न केवल स्त्री के अंगों को ही प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि आपके आदेश पर परदे पर उभरी स्त्री अपने कपड़े पहनने व उतारने भी लगेगी। आप एक कदम आगे बढ़कर कामक्रीडा को भी परदे पर मनचाहे ढंग से देख सकते हैं। इन दृश्यों के साथ संगीत की भी व्यवस्था है। नग्न फिल्मों से यह इस मायने में भिन्न है कि नग्न फिल्मों में तो आप पहले से रिकार्ड की गयी फिल्म के दृश्यों को ही देख सकते हैं, लेकिन इस कामोत्तेजक कंप्यूटर के जरिए उभरे चित्र पहले से रिकार्ड किये हुए नहीं होते, इन्हें आप अपनी रुचि के अनुसार मनचाहा रूप दे सकते हैं।

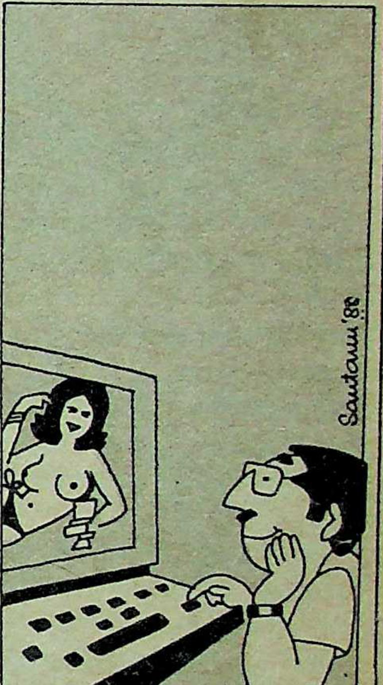

इस कंप्यूटर का नाम है मेकिनतोश कंप्यूटर, जो भारत में उपलब्ध है। इसकी डिस्क २९.९५ डालर से ४९.९५ डालर की कीमत में मिल सकती है।

—अभय अग्रवाल

देश

१ अप्रैल : भारत ने 'शारजाह कप' जीता। बिहार सरकार ने पड़रिया बलात्कार कांड की जांच के लिए उच्च न्यायालय से कहा।

२ अप्रैल : वन्य जीव विशेषज्ञ प्रकृति चंद्र बरुआ का निधन।

३ अप्रैल : जम्मू-कश्मीर और पंजाब से लगी पाक सीमा सीलबंद।

४ अप्रैल : प्रख्यात पुरातत्वविद डा० विष्णुश्रीधर वाकणकर का निधन।

५ अप्रैल : कानपुर में आतंकवादियों द्वारा इंका विधायक विलायती राम कत्याल और उनके सुरक्षाकर्मी की हत्या।

६ अप्रैल : आगरा में भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शुरू।

७ अप्रैल : पत्रकार कुलदीप नैयर को 'हल्दी घाटी पुरस्कार' देने की घोषणा। मुकुल वासनिक युवक इंका के नये अध्यक्ष निर्वाचित।

८ अप्रैल : आगरा में भाजपा का अधिवेशन शुरू, लालकृष्ण अडवाणी फिर अध्यक्ष चुने गये।

९ अप्रैल : पंजाब में आतंकवादियों के पास स्टिंगर मिसाइल होने के सबूत।

१० अप्रैल : हरियाणा के भाकपा विधायक हरनाम सिंह के तीन परिवार जनों की आतंकवादियों द्वारा हत्या। स्वर्ण मंदिर के आस-पास सुरक्षा बलों का मोर्चा।

११ अप्रैल : ३५वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। वरिष्ठ फिल्मकार राज कपूर दादा साहब फालके पुरस्कार से सम्मानित। जम्मू कश्मीर में पाकपरस्तों द्वारा पाकिस्तान के शास्त्रागार में लगी आग की सहानुभूति में हड़ताल करवाने के कारण दंगे।

१२ अप्रैल : सिखों से एक होने की अकालतख्त के जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े की अपील। 'यूएनआई' के अमृतसर स्थित संवाददाता कुलदीप सिंह अरोड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार।

१३ अप्रैल : भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ी सोमनाथ चोपड़ा का निधन। रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत के दौरे के समय सियाचिन में गोला-बारी। किरण बेदी वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की उपनिदेशक नियुक्त।

१४ अप्रैल : जेल में बंद भाई मनजीत सिंह की अगले चुनाव होने तक 'एआईएसएसएफ' के अध्यक्ष पद पर अचानक नियुक्ति की घोषणा।

१५ अप्रैल : आतंकवादियों ने पंजाब में शस्त्रागार लूटा और ५० व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। विन चड्ढा संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष हाजिर। १५००० मील लंबी आस्ट्रेलिया की यात्रा करनेवाली 'वरुण' पाल नौका भारत वापस।

रतीय ज
राष्ट्रीय अधिवेशन दि
दीनदयाल धाम-

लालकृष्ण अडवाणी

जयवर्धने

अफगान – राष्ट्रपति नजीबुल्लाह

विदेश

१ अप्रैल : पूरे विश्व के देशों को नशीले पदार्थ की
करनेवाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़।

२ अप्रैल : अमरीका द्वारा १३०० सैनिकों को पनामा
भेजने का निर्णय। ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच नाभिकीय सुरक्षा संबंधी समझौता।

३ अप्रैल : जिनेवा में अफगान समझौते के प्रारूप की तैयारी पूर्ण। सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

४ अप्रैल : पाकिस्तान में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता दि
कुमार एवं उनकी पत्नी सायराबानो का उनके गृहनगर पेशावर में भव्य स्वागत। बांग्लादेश में इस्लाम को राजकीय धर्म बनाने का व्यापक विरोध।

५ अप्रैल : निकोसिया में ११४ यात्रियों सहित कुवैती विमान का अपहरण

६ अप्रैल : इराकी प्रक्षेपास्त्र के हमले से १५ मरे। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ति जा
रखने का निश्चय।

७ अप्रैल : संपूर्ण विश्व में धूम्रपान निषेध दिवस। पाकिस्तान को अमरीका से ११ और एफ-१६ विमान
५६० प्रक्षेप्यास्त्र।

८ अप्रैल : ८१ वर्षीय यांग शांग चीन के नये राष्ट्रपति निर्वाचित। चाऊ-एन-लाई के दत्तक पुत्र ली पेंग चीन
चौथे प्रधानमंत्री बने।

१० अप्रैल : पाक के एक सैनिक शस्त्रागार में भीषण
से १२०० से भी अधिक लोगों की मृत्यु, ५००० से
घायल। अफगान छापामारों ने एक रूसी विमान को
गिराया, २९ मृत।

११ अप्रैल : श्रीलंका में जयवर्धने की तमिल छापामार नेताओं से वार्ता। भारत में क्रिस्ट्राफ कोनारो आस्ट्रि
के नये राजदूत नियुक्त।

१२ अप्रैल : दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खि
सतत सघर्ष करने वाले विश्वविख्यात साहित्यकार ए
पैटन का निधन।

१३ अप्रैल : अपहृत कुवैत विमान अल्जीयर्स पहुंचा।
में स्थानीय निकाय के चुनावों में हुई हिंसा में ४ मरे
जोहांसबर्ग में विमान दुर्घटना होने से २३ व्यक्तियों
मृत्यु।

१४ अप्रैल : जिनेवा में सोवियत संघ, अमरीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारतीय प्रधानमंत्री रा
गांधी दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे।

१५ अप्रैल : जापान में 'भारत-महोत्सव' आरंभ।

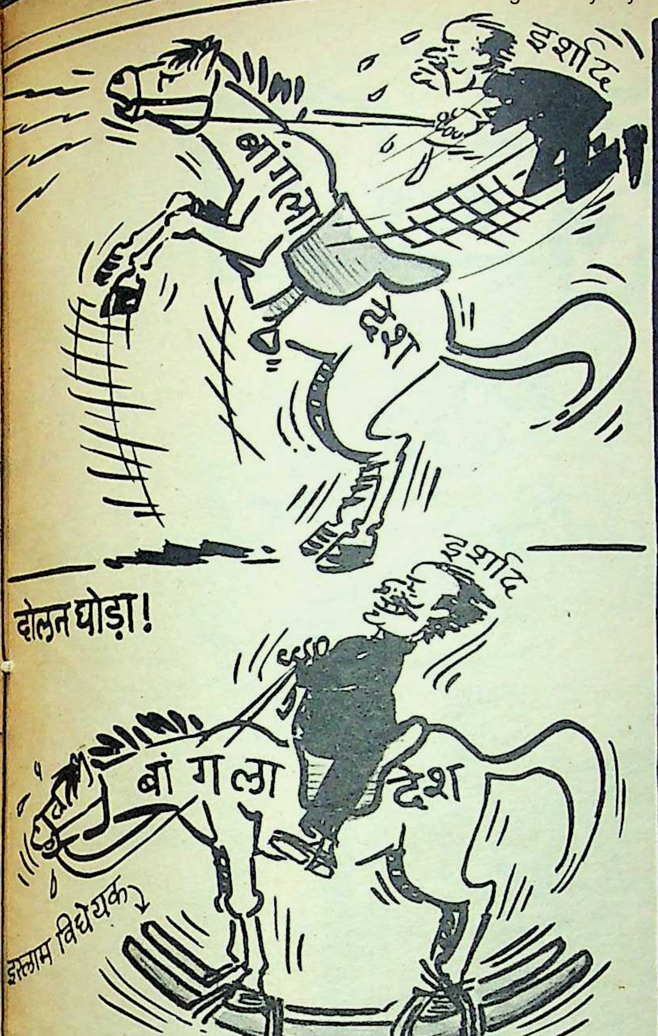
इर्शाद
बांगला देश
दौलत घोड़ा!
इर्शाद
बांगला देश
इस्लाम विधेयक

बांगला देश को इस्लाम राज्य घोषित करने के लिए जनरल इर्शाद संसद में एक विधेयक पेश करेंगे —

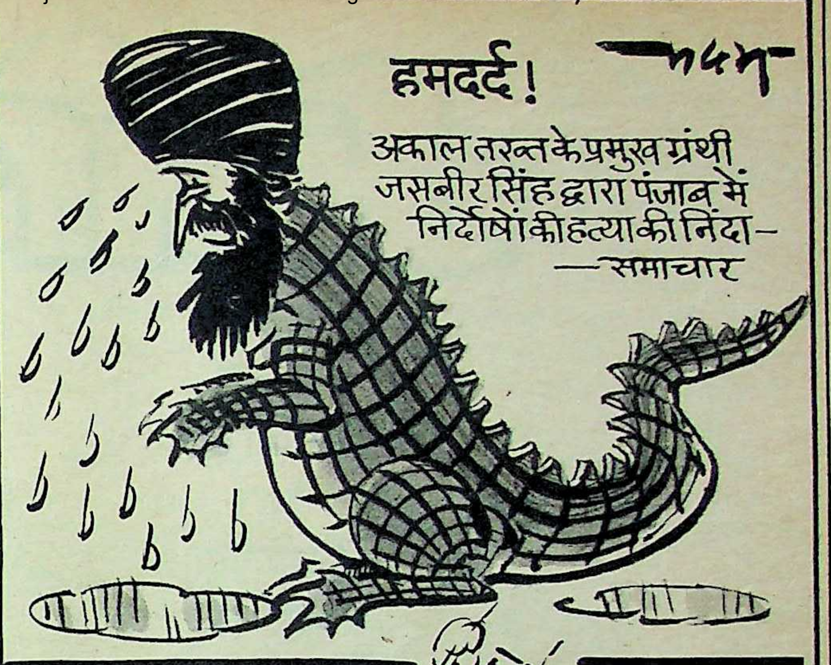

अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी जसबीर सिंह द्वारा पंजाब में निर्दोषों की हत्या की निंदा —
—समाचार

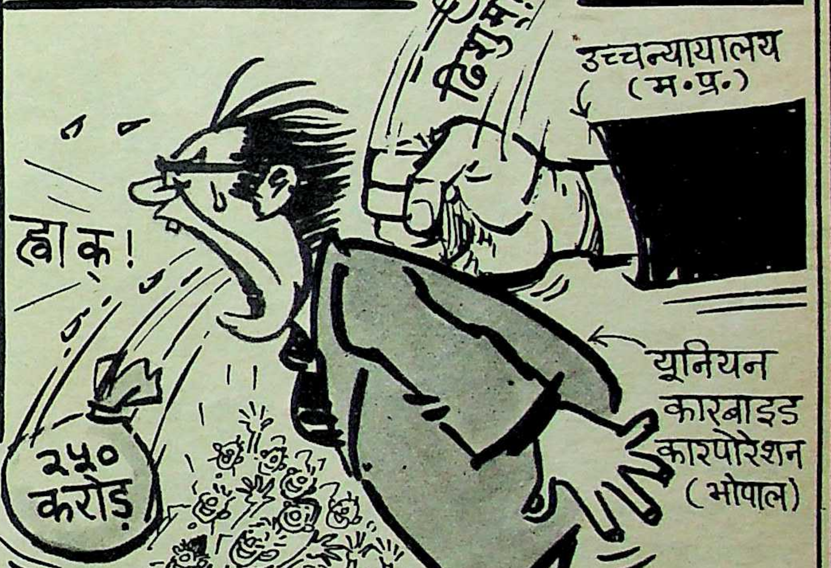
ढिशुम!
उच्चन्यायालय (म॰प्र॰)
हाक!
यूनियन कारबाइड कारपोरेशन (भोपाल)
२५० करोड़

म॰प्र॰ उच्चन्यायालय द्वारा 'यूनियन कारबाइड' को भोपाल गैस रिसनकांड के पीड़ितों को २५० करोड़ की अंतरिम राहत का निर्देश —

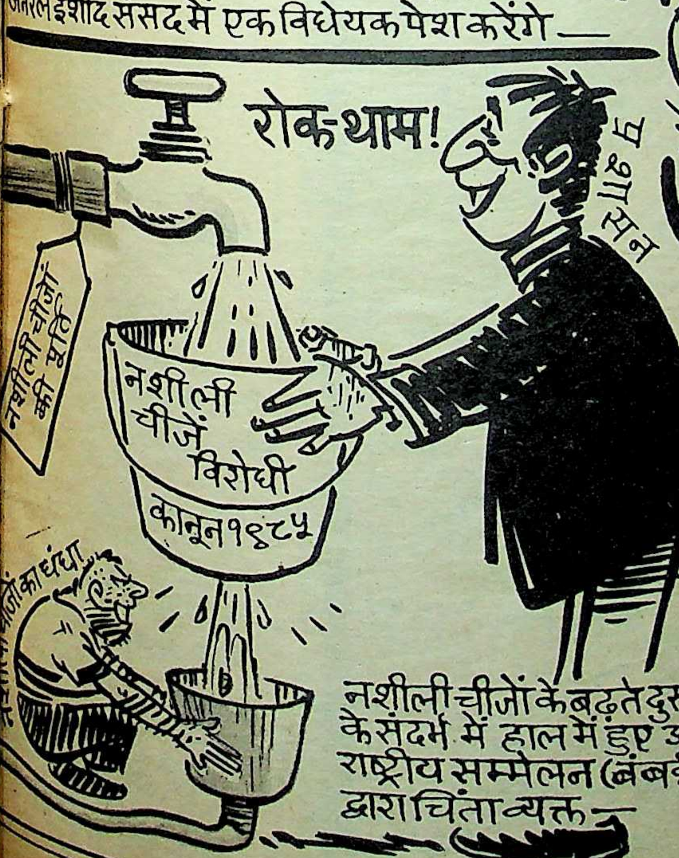
रोक-थाम!
प्रशासन
नशीली चीजों की पूर्ति
नशीली चीजें विरोधी कानून १९८५
नशीली चीजों का धंधा

नशीली चीजों के बढ़ते दुरुपयोग के संदर्भ में हाल में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (बंबई) द्वारा चिंता व्यक्त —

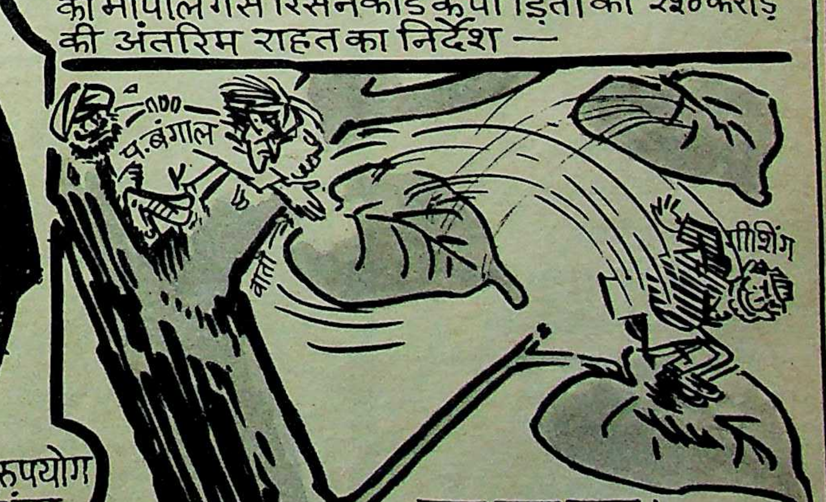
प॰ बंगाल
वार्ता
गीशिंग

...हम पात पात!

अब गीशिंग गोरखा प्रदेश से कम के लिए वार्ता को तैयार नहीं —

मई के प्रथम सप्ताह तक प्रकाश्य

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

सौन्दर्य विशेषांक

सौन्दर्य
विशेषज्ञों द्वारा
तैयार
किया गया
विशेषांक

अंक के विशेष आकर्षण

- अपने भीतर सोयी सुन्दरी को जगाइये
- घरेलू मास्क का जादुई चमत्कार
- आपके चेहरे का निखार : अभिनेत्री स्वप्ना के विचार
- कैसे दिखाते हैं अभिनेत्रियों को खूबसूरत ?
- आइये, हम आपको सुन्दर बना दें
- क्या खायें, कि दिलकश लगें
- उम्र बढ़ती रही, शबाब बढ़ता रहा
- झुर्रियों से कैसे बचें ?
- मोटापा घटायें, सौत से बचें
- 'आज खा लें, कल से डाइटिंग करेंगे'
- कैसे करें सार-संभाल बालों की
- नये-निराले बीस हेयर-स्टाइल
- नजर भरके देखने वाली आंखें
- सुडौल पुष्ट वक्ष के लिए व्यायाम
- सुन्दर बनाने की तकनीक : कॉस्मेटिक सर्जरी
- क्या हार्मोन्स स्वास्थ्य व सौंदर्य को प्रभावित करते हैं
- क्या कहते हैं वे लोग, जो ब्यूटी-पार्लर जाते हैं ?

आवरण कथा :

सुन्दर नारी पुरुष की सबसे खूबसूरत कमजोरी

सुन्दर नारी पुरुष की कमजोरी होती हैं—इस बात में आखिर सच्चाई कितनी है ? और यदि सच्चाई है भी, तो खूबसूरती की परिभाषा क्या है ? स्त्री की कैसी शख्सियत पुरुष के लिए कमजोरी बनती है ?

विशिष्ट

अपने आपसे प्यार कीजि
क्या आपके पति चिड़चिड़े हैं
मेरी बातों
मम्मी गुस्सा क्यों हो जाती हैं
डर से डरिये मत
मेरी सुहागरात
'यह कल्पना भी नहीं
चक्रव्यूह : चक्रव्यूह में फंसी नी
व्यंज
पीजिए शीतल, सौन्दर्यवर्द्धक
फिल्म : मिथुन चक्रव
अपनी ही गलती से मारा गया गुल
फैशन : सलवार-कुर्ते नयी सज-धज
फुरसतना
भाभी जान/ अहमद जमाल
कह
एक औरत और टैक्सियां/ सुख
बंगला की सशक्त कहानी :
साथ ही सभी स्थाई

आज ही अप
प्रति सुरक्षित कर

बड़े कि राजा

व से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद से चुनाव ने के लिए अमित बाबू को कारा है, सफेद टोपीवालों की के अमित-बंगले पर मदरफ्त तेज होने लगी है, किन राजनीतिक के जले अमित बाबू ऐसे हैं कि सी को हाथ ही नहीं धरने देते। व दिल्ली दरबार गहरी सोच में हैं कि राजा साहब की शह

गोविल छाया: रयिजीत घटक

मात देने के लिए किस ारे पर चुनाव का ताज नायें जो हजारों-लाखों का जमा बिना गाजे-बाजे के ही गा ले।

यों पटना के बिहारी बाबू फेद टोपी धारियों को देख कर रा जरूरत से ज्यादा चौकन्ने हो ये हैं और अपने रामायण-भवन द्वार खोल कर बैठ गये हैं कि ावी-टिकट की पोटली लिये सुदामा उनके ठौर पर गलती ी सही कहीं आ बिराजे, तो के पौ-बारह हो जायें। यों तो ाजी कहिन' स्टाइल में वह वीर बहादुर सिंह का ाटी पर सम्मान कराने ए तैयार हैं।

लेकिन लगता है, चुनाव की ी वाले सुदामा को किसी ने ा दिया है और सुझा दिया है 'रामायण' के बिहारी बाबू के बजाय अगर 'रामायण' के कलियुगी राम (अरुण गोविल) को सीता (दीपिका) के साथ राम-सीता के बाने में प्रयागराज पहुंचा भर दो—केवट से लेकर खेवट तक सारे इलाहाबादियों का मजमा उनके दर्शनार्थ जुट जायेगा और अपने सारे वोट बिना नोट के उन पर न्यौछावर कर धन्य-धन्य हो उठेंगे। अब यह दूसरी बात है कि दिल्ली दरबार को यह चुनावी काट भरमायेगी या नहीं! चाहें तो राजा साहब भी इस काट को झटक सकते हैं।

बेचारे मिथुन

फिल्म के परदे पर बड़े-बड़े धांसू डायलाग बोलकर सिनेमा हाल में चवन्नियां दर्शकों से तालियां-सीटियां बजवाने में माहिर मिथुन चक्रवर्ती को जब सचमुच की जिंदगी में दस बच्चों के सामने बोलने के लिए माइक थमा दिया जाता है, तो उनके पसीने छूटने लगते हैं।

यों पत्रकारों को घास-मूली समझने और हिकारत के चश्मे से देखनेवाले मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'कर्मदाता' को लेकर जब फैजपुर में दंगा हो गया तथा लोगों ने उन्हें 'कम्युनल' के सुनहरे खिताब से अलंकृत करना शुरु किया, तो तालाब में फंसे गजराज की तरह उन्हें संकट-मोचक पत्रकारों की याद आयी। बस, उन्होंने शूटिंग से कैजुअल लीव लेकर अपने धांसू डायलाग रायटर से भाषण लिखवाया और धर्मपत्नी योगिताबाली तथा घर के पिल्लों की फौज को पत्रकार-समूह मानकर रिहर्सल किया, लेकिन पत्रकार सम्मेलन में माइक का

डिंपल कपाड़िया और मिथुन चक्रवर्ती फिल्म 'बीस साल बाद' में छाया: डीआर यादव

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शाम उतर आयी थी। अपने भारी-भरकम कर्घे पर खूबसूरत कालीन बुनती अब्दुल्ला की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। डिज़ाइनदार कालीन में आखिरी टांका लगाते हुए अचानक उन्हें सन् १९७७ की याद हो आयी... जब शाहजहांपुर के कालीन बुनकर बेतरह खस्ताहाल थे। विरासत में प्राप्त हुनर लुप्त हो चला था। उनका सारा उत्साह ही टूट चुका था। उन दिनों ऊनी कालीन का न कोई कद्रदान था, न बाज़ार। तभी आई टी सी त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से उनकी मददगार बनी।

शाहजहांपुर के अब्दुल्ला। इनके हाथों का हुनर इन्हें दो वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा था।

तभी आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से इनकी प्रतिभा को पहचाना और सम्मान दिया।

निर्यात से पहले, कालीनों की जाँच-परख

इस प्राचीन कला-कारीगरी को पुर्नजीवित करने के लिए, आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स की स्थापना की। कर्नल प्रेम सहगल (आइ एन ए ख्यातिप्राप्त) के समर्पित नेतृत्व में, त्रिवेणी ने प्रतिभाशाली, लेकिन गरीब बुनकरों को कच्चा माल और तकनीकी सलाह देकर उनकी मदद की।

सन् १९७७ में कुल ३५ कर्घे थे। आज ४०० से भी ज्यादा कर्घों पर कालीन बुनाई होती है। बुनकरों का पारिश्रमिक भी ४ रुपए से बढ़कर १५० रुपए प्रति वर्ग फीट हो चुका है। उत्पादन क्वालिटी में भी प्रशंसनीय सुधार हुआ है।

त्रिवेणी की कालीनें अब विदेशों को निर्यात की जाती हैं और ८० लाख रुपयों से भी ज्याद विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। आज २५०० से भी अधिक बुनकरों के लिए बेहतर आमदनी, बेहतर जीवन और बेहतर बचत का द्वार खुल गया है। आई टी सी को संतोष है कि यह भारत के कुटीर-उद्योग के विकास में हाथ बंटा रही है।

शंसनीय सुधार

ों को निर्यात
ों से भी ज्याद
है। आज
के लिए बेहतर
हतर बचत का
को संतोष है कि
विकास में हाथ

य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के
दन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार
ों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

र कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी परिवार-नियोजन के साधन आसानी
लब्ध कराते हुए गांव-कस्बों तक में छोटे परिवार और कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के
ा प्रचार-प्रसार कर रही है ।

र शास्त्रीय संगीत : कलकत्ते के संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक के गठबन्धन
ई टी सी ने गुरु-शिष्य परम्परा को जीवित रखा है और देश भर में नयी-नयी संगीत-प्रतिभाओं
साहन दिया है ।

I.T.C. Limited

Contract ITC 45 88 HIN

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

दशानन देखते ही सारा रटा-रटाया भाषण हवा हो गया। भूले भाषणों को जोड़ कर किसी तरह उसे संक्षेप में निबटाया और पहले से तैयार प्रेस रिलीज थमा कर तौलिये से पसीना पोंछने लगे।

ऐसे में अगर उन्हें डिंपल याद आ गयी हो, तो असंभव नहीं, क्योंकि 'बीस साल बाद' भी वह बिना माइक के भाषण देने का दम रखती है। रखे क्यों नहीं, राजेश खन्ना से विवाह के बाद वह हर महीने किसी-न-किसी फैशन बुटीक या ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन जो किया करती है!

नाच सलमा, नाच!

अपने को बीसवीं एवं इक्कीसवीं सदी की मलिका-ए-तरन्नुम माननेवाली सलमा आगा ने अब अपनी ही तान पर नाचना भी शुरू कर दिया है। 'निकाह' की सफलता के बाद जब निर्माताओ ने उससे फिल्मों में नाचने के लिए इसरार किया, तो नचनियों को हिकारत की निगाह से देखने वाली सलमा ने यह कहकर मना कर दिया, "कभी आपने तानसेन या लता मंगेशकर अथवा आशा भोंसले को नाचते हुए देखा है? मेहदी हसन को पैरों में घुंघरू बांध कर ता-थैया-ता-थैया करते हुए पाया है? फिर मैं तो सिंगर-स्टार हूं, मेरे गाने सिर्फ मुझी से गवाइए, मैं सिंगर-सिस्टर्स (लता मंगेशकर ऐंड सिस्टर्स) की यों (चुटकी बजाने का इशारा कर) छुट्टी कर दूंगी!"

सलमा के बड़बोलेपन से क्षुब्ध फिल्म निर्माता अपनी फिल्म से उसी की छुट्टी कर ता-थैया वाली जयाप्रदा एवं श्रीदेवी को साइन करने पहुंच जाते। बंबई फिल्म इंडस्ट्री से लगभग दो दर्जन बार खुदा हाफिज कर कभी पाकिस्तान, तो कभी हालीवुड चली जाने फिर वहां एक नया विवाह या अफेयर रचाकर 'उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आयो' की तर्ज में वापस चली आती और 'मेरो तो बंबई, दूसरो न कोई' की धुन पर फिल्मों में काम शुरू कर देती।

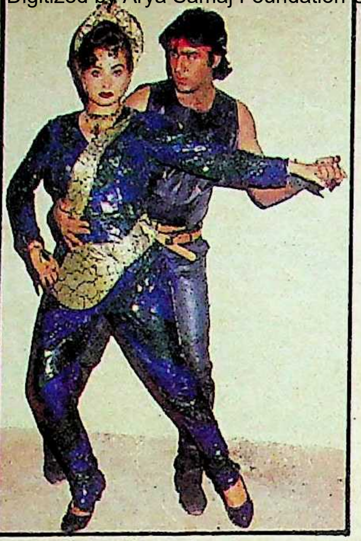

सलमा आगा और सुमीत छाया : महेश जाली

आवागमन के इतने झंझावातों के बाद शायद अब 'मेरो तो अस्थिर चित्त' को नया ज्ञान मिल गया है—अब वह फिल्मों में खुद गाने का हठ नहीं करेगी और निर्देशक के हर इशारे पर हीरो के साथ कदंब-डाल से लेकर नदी-झरने और ताल-तलैया पर भी नाचेगी। और-तो-और जिन सितारों को वह 'कल का बच्चा' कहकर मा के पास दूध पीने के लिए भिजवा देती थी, अब उन्हीं की हीरोइन बनने में भी गौरव हासिल कर रही है—चाहें वह चंकी पांडे हों या सुमीत सहगल!

१८ वर्ष छोटी बेगम

'बुनियाद'—निर्देशक रमेश सिप्पी को अपनी हीरोइनों को पहले तो रिझाने, फिर उनके दिल पर ठेस लगाने की बुरी लत है। कभी वह डिंपल को भरमा कर ठुकरा देते हैं, तो कभी मंगलाजी उर्फ कृतिका को! डिंपल का जख्म अभी सूखा भी नहीं था कि कृतिका का जख्म गहरा होने लगा। डिंपल के घाव को तो वक्त ने मरहम लगाकर भर दिया, लेकिन कृतिका ने घाव के मुकाबले जवाबी घाव देने की रणनीति अपनायी। रमेश सिप्पी के लिए दिल की खिड़की का दरवाजा भेड़ कर अपने से पूरे डेढ़ दर्जन वर्ष बड़े इम्तियाज खान के लिए खोल दिया, जो 'बाबा-एलिफेंट' (अमजद खान) के अग्रज हैं और तीन-तीन निकाहों के सेहरे सिर पर बांध और उतार चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चौड़े-चकले सीने के भीतर दिल के ड्राइंग-रूम में दर्जनों कृतिकाएं 'इन' और 'आउट' हो सकती हैं।

कृतिका देसाई छाया : जितेंद्र आर्य

उम्र में १८ वर्ष तथा कद में डेढ़ फुट छोटी कृतिका इम्तियाज मियां की चौथी बेगम बनने पर फख्र कर सकती है। वह डिंपल और योगिता बाली का उदाहरण भी दे सकती है, जिन्होंने अपने से दुगुने (राजेश खन्ना) तथा तिगुने (किशोर कुमार) उम्र वाले पतियों से विवाह किये। किशोर कुमार योगिता से पहले दो और विवाह कर चुके थे और राजेश खन्ना बिना विवाह किये भी अंजू महेंद्रू के साथ दांपत्य जीवन बिता रहे थे। अब यह दूसरी बात है कि कृतिका इम्तियाज के जिस खाली मकां को आबाद करने जा रही है, वहां अंजू महेंद्रू का आशियाना था, जो दो उजड़े आशियानों की नींव पर बना था।

कृतिका जिस डिंपल और योगिता के उदाहरण सामने रखती है, उनके आशियाने परवान चढ़ने के पहले और बाद में उजड़ चुके थे। लेकिन कृतिका को इस सबक का गम नहीं, क्योंकि वह यह कह सकती है कि वह दिल (ही) क्या जो बार-बार टूटे और जुड़े नहीं!

धूप और छांव

कहावत है—घूरे के भी फिरते हैं फिर वह तो विश्वजीत हैं जिनके बंगले कभी हर सुबह सलामी ब निर्माताओं-वितरकों-निर्देश ऐसा मेला जुटता था कि का पानी पिलाते-पिलाते ह जाता था, लेकिन कोर्निश बजानेवालों की कमर पर नहीं पड़ते थे। उसी बंगले दिन ऐसा आया कि दरवाजे दूर मक्खियां भी भिनभिनाने कतराने और नौकर-चाकर लगे।

विश्वजीत के बंगले से फर्लांग दूर सुरेश ओबेराय चढ़ते सूरज को नमस्कार करनेवाले दरबारियों की आमदरफ्त एक बार इतनी गयी थी कि सुरेश ने 'ओलि शेल' (जहां वह रहते थे) का ग्राउंड फ्लोर ही खरीद लिया। लेकिन भीड़ जब वहां भी अंट नहीं पायी, तो सातवीं मंजिल के अपने फ्लैट को दरबारियों के कोर्निश के लिए छोड़ मय फैमि कहीं और शिफ्ट हो गये। कुछ दिनों के भीतर जब दरबारी मिथुन चक्रवर्ती के मकान पर कोर्निश बजाने के लिए जुटने तो सुरेश ने ग्राउंड फ्लोर का फ बेच दिया और दिन का खाली समय सातवीं मंजिल पर भूले भटके आ पहुंचनेवाले निर्मात की बाट जोहने में वह बिताने और तब एक खाली अभिने (विश्वजीत) ने दूसरे खाली अभिनेता (सुरेश ओबेराय दर्द को समझा और हीरो अपनी पगड़ी उतारकर पर पहना दी और एक फि 'आजा मेरे लाल' बना डा जब फिल्म हिट हो गयी, तो अपना डोर-डम्मर उठाकर हमेशा के लिए कलकत्ता के कूच कर रहे विश्वजीत ने फि बंबई में धूनी रमा ली, क्यों उनके सूने पड़े बंगले और सु की सातवीं मंजिल प दरबारियों की आमदरफ्त हो गयी थी।

—अखबारी

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद-३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय-१०५, रोहित हा
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ११०००१।

छांव
-घूरे के भी
फिर वह तो
जिनके बंगले
ह सलामी ब
तरकों-निर्देश
टता था कि
ाते-पिलाते
किन कोनिश
की कमर पर
। उसी बंगले
या कि दरबार
भी भिनभिना
नौकर-चाकर
ीत के बंगले में
रेश ओबेराय
ो नमस्कार
बारियों की
क बार इतनी
ुरेश ने 'ओलि
ह रहते थे)का
ही खरीद लिया
ब वहां भी अंटे
सातवीं मंजिल
ी दरबारियों के
ए छोड़ मय फ
स्ट हो गये। कुछ
र जब दरबारी
ों के मकान पर
के लिए जुटने
ाउंड फ्लोर का म
र दिन का खाली
मंजिल पर भूले
बनेवाले निमात
में वह बिताने
खाली अभिने
ने दूसरे खाली
श ओबेराय
और हीरो
उतारकर
और एक फि
ल' बना डा
ट हो गयी,
मर उठाकर
कलकत्ता के
विश्वजीत ने फि
रमा ली, क्यों
बंगले और मु
जल प
आमदरफ्त
—अखबार
५, रोहित हा

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

• प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८९, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, • दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१९७५३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, पोरवाल अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१ फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७६०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६११५८ बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२१५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ९२ (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २११०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक १२ ३० जून, १९८८

13162
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

आवरण कथा
१३

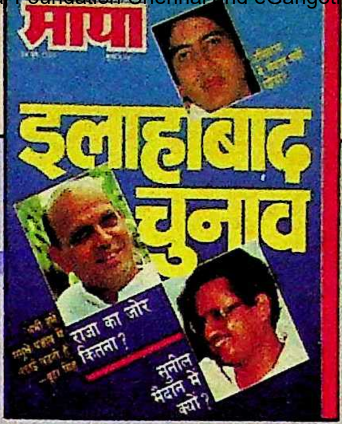

पूरे देश की आंखें इलाहाबाद चुनाव के नतीजे पर लगी हुई हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह और वीपी सिंह सहित विपक्ष के भाग्य का फैसला होगा। पर नतीजे के पूर्व इस चुनाव में अमिताभ के न उतरने से क्या कांग्रेस पहली लड़ाई हार गयी? वह चुनाव-मैदान से बाहर क्यों कर दिये गये, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने वायदे के खिलाफ अमिताभ के बजाय सुनील शास्त्री से क्यों टकरा रहे हैं? पलड़ा किसका भारी है?

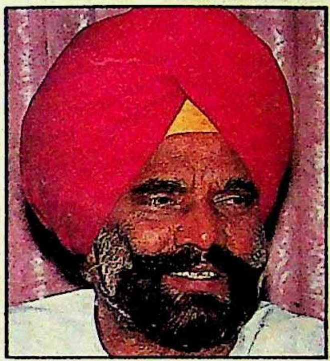

४० बूटा सिंह
स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों के सफाये के बाद पंजाब के हालात पर गृहमंत्री बूटा सिंह से विस्तृत साक्षात्कार

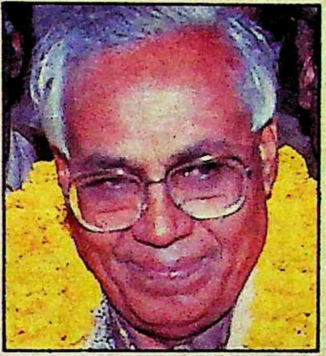

५४ बिहार
विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा और मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद आपस में क्यों टकरा रहे हैं?

९० सोनम और सुजाता
अभिनेत्री सोनम में ऐसी क्या खास बात है कि उसने प्रतिभा की धनी सुजाता मेहता को बहुत पीछे छोड़ दिया है?

७४ फिलिस्तीन
फिलिस्तीनी ४० वर्षों से इस्रायल से खूनी जंग क्यों लड़ रहे हैं? आखिर यह फिलिस्तीनी समस्या है क्या?

४६ शिव सेना
औरंगाबाद में दंगे क्यों भड़के? इसके लिए शिव सेना कहां तक जिम्मेदार है?

६२ उत्तर प्रदेश
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की 'अयोध्या मार्च' की घोषणा ने कैसा सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है?

देश/राजस्थान-उपचुनाव: कांटे की लड़ाई ३३
देश/मप्र-खरसिया उपचुनाव: अर्जुन सिंह की स्थिति ३४
देश/उप्र-छपरौली टांडा उपचुनाव: विपक्ष का जोर ३५
अभिमत/सत्यपाल डांग: आपरेशन ब्लैक थंडर और उसके बाद ४४
दिल्ली/एनएसयूआई का अंतर्कलह ५०
बिहार/विवाद, वस्तु संरक्षण का ५३
राजस्थान/गृहमंत्री की कृपा एक पुलिस अधीक्षक पर! ५७
राजस्थान/हरिदेव जोशी: गहलौत के खिलाफ जंग की शुरुआत ६०
उत्तर प्रदेश/प्रो० अग्रवाल की हत्या का रहस्य? ६१
तथाकथित/संसद की आबरू खतरे में ६६
अर्थतंत्र/श्रीराम उद्योग समूह संकट में? ६९
अपराध/माफिया डान: सिंहासन खाली है... ८०
दूरदर्शन/बासु भट्टाचार्य से बातचीत ९५
स्त्री/महिलाएं किसके साथ हैं? ९९
प्रसंगवश: विश्व युवा छात्र आंदोलन में भारत की भूमिका १०१
मेहमान: जिसानो १०४

आवरण पारदर्शी
सुनील सक्सेना (ओपी सिंह)
[illegible]

कई वर्षों बाद, हैदराबाद के करीब कुरनूल में, दूर-दूर तक हंसते झूमते सूरजमुखी फूलों की कतारें नज़र आती हैं। अपने खेत में, इन फूलों को निहारते हुए, रघुराम रेड्डी की आँखें ख़ुशी से चमक उठीं। जल्दी ही, अब सुनहरी फसल लहलहा उठेगी। इस बार का मौसम उन्हें बेहद खुशनुमा लगा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सूरजमुखी की खेती आसान और मुनाफेभरी है। यह फसल न तो बारिश की मोहताज है, न ही इसके लिए ज़रूरत से ज्यादा क़ीमती खाद या किटाणुनाशक दवाए ज़रूरी हैं। लहलहाती फसल की उम्मीद में रघुराम ने अपनी अधिकांश ज़मीन पर सूरजमुखी की खेती का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी और दो वर्षीय बेटे के सुखद भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्हें पिछले साल की याद हो आती है, जब आइ टी सी उनकी मदद के लिए आगे आयी...

कुरनूल के रघुराम रेड्डी। बारिश के अभाव में अपने सूखे खेतों को देखकर वे आठ-आठ आँसू बहाते थे।

तभी आई टी सी की बीज-यूनिट की मदद से उनके खेतों में सुनहरी फसलें झूम उठीं।

शोध द्वारा तकनीक की यात्रा... तम्बाकू से तैल बीजों तक

लगभग आठ दशक से आइ टी सी तम्बाकू की खेती करनेवाले किसान भाइयों को बेहतर क़िस्म के बीज, खाद और असरदार किटाणुनाशक दवाएं प्रदान करती आयी है। अब राष्ट्रीय कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में तैल-बीजों के उत्पादन और मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए आइ टी सी की बीज-यूनिट कृषकों को खेती की आधुनिक तकनीक सिखा रही है।

आई टी सी के शोध-केन्द्र आंध्र प्रदेश और गुजरात में विभिन्न तैल-बीजों की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं। यहां सूरजमुखी, कुसुम, बिनौले, रेंड़ी की कई किस्मों के बीजों के मेल से पैदावार कई गुना बढ़ गयी है। आइ टी सी किसानों की फसलों की अच्छी क़ीमत भी चुकाएगी और इस तरह लगभग १०,००० किसानों को लाभ पहुंचेगा।

आई टी सी अपने मार्कीटिंग तजुर्बे और विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा खाने के तेलों को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। देश के पिछड़े इलाकों में तेल निकालनेवाले कारखानों की स्थापना में भी आइ टी सी सहयोगी साबित होगी और रोज़गार के अधिकाधिक मौकें प्रदान करेगी।

ार कई
की फसलों
तरह
हुंचेगा।
र विस्तृत
ग्राहकों
छड़े
की
बत होगी
न करेगी।

मनुष्य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

परिवार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी परिवार-नियोजन के साधन आसानी से उपलब्ध कराते हुए गांव-कस्बों तक में छोटे परिवार और कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के लाभ का प्रचार-प्रसार कर रही है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत : कलकत्ते के संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक के गठबन्धन द्वारा आई टी सी ने गुरु-शिष्य परम्परा को जीवित रखा है और देश भर में नयी-नयी संगीत-प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है।

कुटीर-उद्योग : शाहजहांपुर में आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिए कालीन-बुनाई उद्योग को पुर्नजीवित किया ताकि २५०० से भी ज्यादा परिवार बेहतर कमा सकें, बेहतर जीवन जी सकें। कालीन निर्यात द्वारा आई टी सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है।

I.T.C. Limited

Contract. ITC 89.88 HIN

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

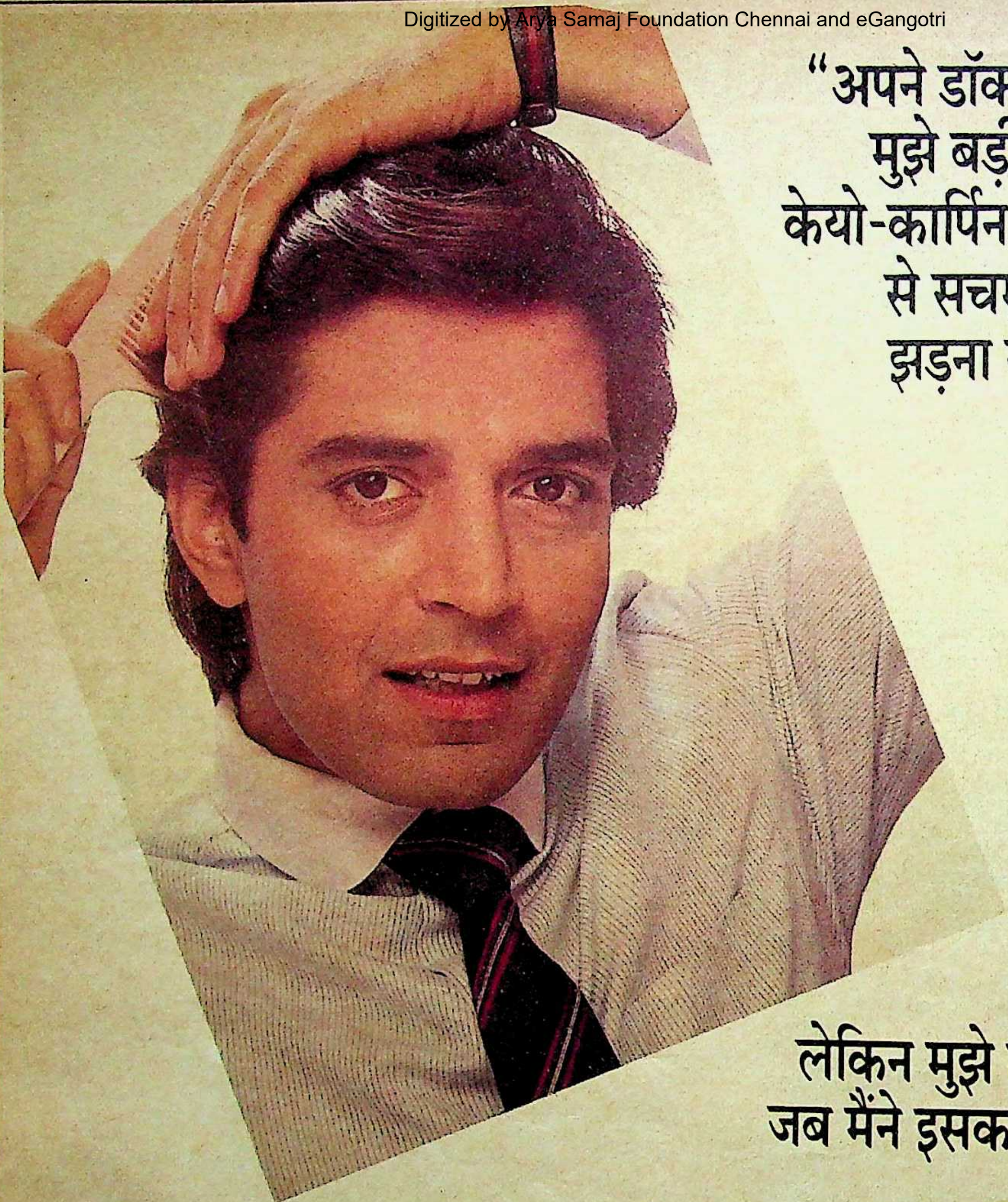

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढिया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
CONTAINING PROTEIN, VITAMINS AND CO-ENZYMES

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

सिंधिया-अर्जुन जंग: राजीव किसके साथ?

बदरंग जंग

'माया' का जून प्रथम अंक मिला। आवरण कथा 'सिंधिया-अर्जुन जंग : राजीव किसके साथ ? बेमतलब लगी। यह समझ में ही नहीं आया कि रिपोर्टर कहना क्या चाहते हैं। यह कौन नहीं जानता कि आजकल अर्जुन सिंह पर हाई कमान की वक्र दृष्टि है। वैसे भी कांग्रेसी अपने आप में विरोधाभास इसलिए पैदा करते हैं कि जनता की नजर विपक्ष पर न रहकर कांग्रेस पर ही रहे।

इस वार की आवरण कथा पढ़कर बड़ा धक्का-सा लगा कि 'माया' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने ऐसे लचर विषय पर आवरण कथा क्यों आयोजित की ? इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि माधव राव सिंधिया पूरी आवरण कथा के केंद्र बिन्दु हैं, जबकि उनका साक्षात्कार ही लुप्त है। एक तो कथा वैसे ही लचर थी, ऊपर से एकांगी भी हो गयी है। बड़े बचकाने ढंग से कथा का विकास हुआ है। कोई ऐसे तथ्य या तर्क भी नहीं हैं कि कथा में वजन आ सके। कम-से-कम 'माया' से यह उम्मीद नहीं थी। **—आदित्य कुमार गोस्वामी, कस्टम अप्रेजर, बंबई**

'माया' के १५ जून वाले अंक में सिंधिया-अर्जुन जंग : राजीव किसके साथ ? सचमुच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एवं रेल राज्यमंत्री माधव राव सिंधिया अपने को एक दूसरे से वेहतर नेतृत्व देनेवाला कहने के चक्कर में लड़ रहे हैं। जब अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल एवं संचार मंत्री थे, तो अपनी मप्र की यात्रा में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को अस्थिर करने का प्रयास करते रहे। और अब श्री सिंधिया एवं वोरा मप्र की यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें अर्जुन सिंह के विरोधी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बस ठीक-ठाक ही रही, यह कथा। **—भरत जैन, १७/१३६, शास्त्री वार्ड, सागर, मप्र**

कामत बनाम वासनिक

३१ मई की 'माया' में 'कामत का पतन और वासनिक का उत्थान' पढ़कर जैसे लगा कि जातिवाद करने में आप पत्रकार भी पीछे नहीं हैं। मुकुल वासनिक को २८ वर्षीय अनुसूचित जाति का युवक कहकर आपने अपनी जातिवादिता स्पष्ट कर दी। अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है, तो उसकी जाति का तिलमात्र भी उल्लेख आपके लेखों में या पत्रिका में नहीं मिलता। लेकिन अगर आदिवासी या अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर आया, तो बस शुरू हो जाता है उसकी जाति का उल्लेख करना और नौसिखिया जैसे शब्दों का प्रयोग करना। माना कि चार दशकों में इनकी स्थिति दयनीय थी, लेकिन आज हालात पूर्णतः उलटे हैं। तथाकथित उच्चजाति वालों के मुकाबले आज अनुसूचित समाज के युवक ही सुशिक्षित और संगठित मिलेंगे। यकीन न हो, तो मार्केटिंग और रिसर्च ग्रुप से सर्वेक्षण करवा लीजिए। **—सुभाष दाभेकट, ठवेर नगर, उत्तर नागपुर**

खबरों के आगे, खबरों के पीछे

'माया' ३१ मई, १९८८ अंक में स्तंभ 'खबरों के आगे, खबरों के पीछे' के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट वीर बहादुर बनाम ब्रह्मदत्त पढ़ा। इसे पढ़ कर ऐसा लगा कि खोजी पत्रकारिता की आड़ में पीत पत्रकारिता का मुखौटा लगाकर निहित स्वार्थों की पूर्ति करने की होड़ में आपकी पत्रिका भी अब किसी से पीछे नहीं है। मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का स्तुति गान करने में आपने रीति कालीन चारणों को भी मात दे दी है। प्रत्येक अंक में किसी-न-किसी प्रकार से वीर बहादुर सिंह की वंदना और उनके कथित विरोधियों एवं प्रतिद्वंद्वियों की भर्त्सना अवश्य देखने को मिलती है। आपने एक स्तंभ अपने पाठकों की चिट्ठियां प्रकाशित करने का भी बना रखा है। लेकिन मुझे खेद है कि इस स्तंभ के अंतर्गत केवल उन्हीं पाठकों के पत्र प्रकाशित होते

किरण बेदी होने का मतलब

'माया' (३१ मई अंक) में दी गयी आवरण कथा 'किरण बेदी : देश की सर्वाधिक चर्चित पुलिस अधिकारी' पर हमें देश के विभिन्न कोनों से पाठकों के काफी संख्या में पत्र मिले हैं। पत्र को भेजने वाले पाठकों में से अधिकतर पाठक जहां किरण बेदी के व्यक्तित्व को अनुकरणीय और प्रशंसनीय बतलाते हैं, वहीं कुछ पाठकों ने किरण बेदी की कार्यशैली को अधिकारों का अतिक्रमण बतलाया है। परंतु कुछ एक को छोड़कर सभी पाठकों ने उनके साहस एवं उपलब्धियों को सराहा ही है।

जिला विलासपुर के रहनेवाले सुरेश सोनी ने जहां उनकी बराबरी 'झांसी वाली रानी' से किया है, वहीं मुंगेर (बिहार) के प्रणय कुमार मिश्र उनको बात-बात पर लाठीचार्ज करनेवाली और कानून का मनमाना प्रयोग करने वाली बताते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण शायद अतिवादी हैं, परंतु सामान्य पाठक अगर किरण बेदी के अदम्य साहस का कायल है, तो वह शायद गलत नहीं है।

'माया' को पाठकों से मिली प्रतिक्रियाओं से एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है। वह यह कि दिल्ली, जहां पर किरण बेदी ने अपने सेवाकाल के कई साल बिताये, से किसी भी पाठक की प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। इसको किस तरह से लिया जाये—क्या दिल्ली की जनता इस सारे प्रकरण से उदासीन है ? या वहां की जनता ने उनके स्थानांतरण को मूक सहमति प्रदान किया है ?

किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राज्य सेवाएं हों, खेल और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र हों या वैज्ञानिक उपलब्धियां हों, इनमें सर्वप्रथम उपलब्धि पाने वाले चर्चा एवं सम्मान का विषय बन ही जाते हैं। अगर किरण बेदी की ख्याति में इसका भी योगदान रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। कटनी की अंजू कुमारी अग्रवाल का तो मानना है कि उनका प्रथम आईपीएस अधिकारी होना ही लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाता। कैसे पुरुष इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि इससे उनके पुरुषोचित अहं को ठेस जो लगती है। फिर भेजी गयी प्रतिक्रियाओं से यह भी पता चलता है कि पाठक उनके स्थानांतरण को एक ईमानदार अधिकारी को परेशान और नीचा दिखाने का बायस मानते हैं। इनमें भोजपुर के अक्षय कुमार द्विवेदी, उज्जैन के कुश आर मेहता, धनबाद के चितरंजन कुमार, भरतपुर के दुली चंद्र लोढ़ा, चित्तौड़गढ़ के नरेश ठक्कर आदि हैं। ये सभी पाठक सरकार के किरण बेदी के प्रति अपनाये गये रुख को उचित नहीं मानते तथा 'ईमानदार अधिकारियों की कमी इन्हीं सब कारणों से होती है', ऐसा इन सब पाठकों का मानना है। इस विचार से भी असहमत नहीं हुआ जा सकता। आये दिन सरकार के रवैये से परेशान होकर अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र देने की खबरें आती ही रहती हैं।

कुछ पाठकों का तो यह भी मानना है कि उनके स्थानांतरण और नारकोटिक्स विभाग में उपनिदेशक के पद पर नियुक्ति से उनकी प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आने वाली। राम नरेश मिश्रा विद्यार्थी ने तो अपने पत्र में विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य की हमेशा विजय हुई है और इस बार भी होगी। वह 'माया' के इस विचार से भी सहमत हैं कि किरण बेदी सफलता का पर्याय बन चुकी हैं।

पाठकों का एक वर्ग इस सारे प्रकरण को राजनीतिक दांव-पेंचों का खेल मानता हैं। वे वकीलों द्वारा किये गये व्यवहार को भी अपेक्षित नहीं मानते। बरौनी के नलिनी कुमार तो लिखते हैं, "वकीलों की इस घटिया हरकत की जितनी भी निंदा की जा सकती हो, की जानी चाहिए।" उन्होंने आगे (शायद भावावेश में आकर) उनको भारत की 'जोन आफ आर्क' तक बता दिया। धनबाद के चितरंजन कुमार तो वकीलों पर आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं।

ये मिली-जुली प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि यदि आम जनता से जनमत लिया जाये, तो किरण बेदी के पक्ष में जनमत अधिक होगा। उन्होंने जो भी कार्य किये हैं, वे बोझिल रहे हैं—ऐसे ही पुलिस अधिकारियों की इस समाज को जरूरत है—जो कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं—बिना किसी दबाव के। पुलिस और वकील को कानूनी व्यवस्था की दो भुजाएं माननेवाली किरण बेदी पर शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कानून की कालीकोट पहननेवालों के साथ जानबूझ कर सख्त रवैया अपनाया। उनका जो फर्ज बनता था—वही किया। फिर जिस मामले को लेकर वकीलों ने 'ऐतिहासिक' लम्बी हड़ताल चलायी—उसे न्याय पाने का सही रास्ता कहना क्या उचित है ? वकील और पुलिस कानून के रक्षक हैं। इसकी तस्वीर न बदले, यह दोनों पक्षों को सोचना होगा।

हैं, जो आपकी पत्रिका की चाटुकारिता व प्रशंसा करते हैं।—**विमलेन्दु भूषण पाण्डेय, सिंहपुर, ज्ञानपुर, वाराणसी**

राजेंद्र राठौड़ का मत

'माया' के ३१ मई, १९८८ के अंक में ओम सैनी ने अपनी रिपोर्ट में मुझे जिस तरह से सती प्रथा का समर्थक ठहराया है, वह बहुत शर्मनाक है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पौराणिक अर्थों में मैं सती मान्यता का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी महिला के पति के देहांत के बाद उसे उसके साथ जल जाने का कुत्सित प्रोत्साहन देने का मैं हामी नहीं। कांग्रेस-इ अपने दुष्कर्मों से जनता में जगह खो रही है। इसे मुझ जैसे जन कार्यकर्ता को बदनाम करके नहीं बचाया जा सकता।—**राजेंद्र राठौड़, २७, म्युजियम रोड, मोती डूंगरी रोड, जयपुर**

मेनका के लिए एक खत

मैं इस पत्र द्वारा जनता पार्टी की महासचिव श्रीमती मेनका गांधी द्वारा 'माया' पत्रिका में दिये गये साक्षात्कार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमती मेनका गांधी ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि युवा जनता एक सुप्त संगठन है, जैसे युवा कांग्रेस संजय गांधी के जमाने में थी और इस संगठन को ऐसा रंग व रूप देना होगा जैसा संजय गांधी के जमाने में दिया गया था। इस तरह के विचार समय-समय पर विभिन्न साक्षात्कारों में पहले भी व्यक्त किये जा चुके हैं।

श्रीमती मेनकाजी के इन विचारों की वजह से युवा जनता के साथियों में काफी गुस्सा और तनाव पैदा हो रहा है। इस आशय के पत्र और टेलीफोन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जब श्रीमती मेनका गांधी जनता पार्टी में शामिल हुई थीं, तो हम लोगों ने ऐसा माना था कि वह जनता पार्टी और युवा जनता के मूल विचारों को स्वीकार करके ही शामिल हो रही हैं। जनता पार्टी और युवा जनता के संविधान में खास तौर से यह बात स्पष्ट की गयी है कि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मागांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा देश के आगे रखे आदर्शों और मूल्यों में निष्ठा रखते हैं और समग्र क्रांति लाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इस कार्य को शांतिपूर्ण साधनों से ही पूरा करना होगा, जिसमें अहिंसा और सत्याग्रह मूलतः इसके आधार हैं।

जहां तक मेनकाजी और संजय के रिश्तों का सवाल है, हम उनका आदर करते हैं। पर राजनीति में संजय गांधी आजादी और लोकतंत्र को समाप्त करने वाला फासीवादी सोच का नाम और कर्म है। संजय गांधी ने गुंडावाद, आतंक और हिंसा का सहारा लेकर राष्ट्र पर हावी होने की कोशिश की। उनकी वजह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, चौधरी साहब तथा चंद्रशेखरजी के साथ-साथ लाखों लोगों को जेलों में बंद होना पड़ा। आपातकाल के दौरान श्रीमती स्नेहलता रेड्डी, हश्मत लोहिया आदि की जेल में जानें भी गयीं। हम लोग राजनीति में परंपरा का विरोध करने के लिए आये तथा पेरोल को ठुकरा कर मीसा में बंद रहे। आज अगर हमसे संजय गांधी के विचारों को अपनाने के लिए कहा जायेगा, तो उसका हम प्रतिकार करेंगे।

मैं यहां यह रेखांकित करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि युवा जनता सुसुप्त अवस्था में है। यह बात निराधार और झूठ है। युवा जनता देश में एकमात्र युवा संगठन है, जिसने पिछले दशक में कुछ मूल सवालों को लेकर संघर्ष किया। बेरोजगारी के सवाल पर देश भर में दसियों हजार लोग जेलों में बंद रहे। पूर्वांचल में शिक्षा में बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ ओम प्रकाश जैसे साथी ने जान जोखिम में डालकर शिक्षा संस्थानों के लोकतंत्रीकरण की लड़ाई लड़ी और आज भी जेल में बंद हैं। विश्वविद्यालयों में औपनिवेशिक शिक्षा की होली जलायी गयी। दून स्कूल पर तालाबंदी की गयी। जलते हुए पंजाब में शांति के लिए निहत्थे अमृतसर से दिल्ली तक पद-यात्रा की गयी। भक्त चरण दास जैसे साथियों ने भूख और अकाल के खिलाफ कालाहांडी में संघर्ष किया। रामविलास पासवान ने दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की आवाज देश भर में बुलंद की।

कृपया मेनकाजी यह भी बताने का कष्ट करें कि उनकी वैचारिक और कर्म के धरातल पर क्या उपलब्धियां रहीं। मैं समझता हूं कि उनका संगठन ही निष्प्राण, निर्जीव और अप्रासंगिक बन चुका था, इसीलिए उन्होंने जनता पार्टी में विलय किया। इनके आते ही संजय मंच के साथियों ने अनुशासनहीनता का परिचय भी दे दिया।

—**सुधींद्र भदौरिया, अध्यक्ष युवा जनता, ७, जंतर मंतर रोड, नयी दिल्ली**

कमलापति त्रिपाठी

कांशीराम

सुनील दत्त

अमिताभ के पास और काम भी करने को है और वह व्यस्त हैं।—**राजीव गांधी, अमिताभ के चुनाव न लड़ने का कारण बताते हुए**

इंदिरा गांधी ने राज्य स्तर के नेताओं का प्रभाव कम करके उन्हें काट-छांट कर ऐसा बौना बना दिया था कि वे संगठन और सरकार को ताकत देने में अक्षम हो गये थे।—**कमलापति त्रिपाठी**

वीपी सिंह की हार तय है। इलाहाबाद में पूरी कांग्रेस उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गयी है। अमिताभ से अगर वह डेढ़ लाख से हारते, तो सुनील शास्त्री से वह एक लाख वोटों से हारेंगे। **—वीर बहादुर सिंह**

हम न तो बोफोर्स को रिहा कर सकते हैं और न उसे बिना दंडित किये हुए जाने दे सकते हैं।—**पूर्व रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह**

बाज और फाख्ताओं की बात मत कीजिए। हम यहां विदेश नीति चला रहे हैं न कि कोई पक्षी विहार।—**नटवर सिंह, पाकिस्तान नीति पर**

मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह सुनील शास्त्री का पूरा समर्थन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।—**कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद**

मैं ही अकेला वह वाममार्गी हूं जो गरीबों के कल्याण के बारे में चिंतित है। बाकी सब उपदेश देते हैं, जबकि मैं अमल करता हूं।—**आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रामाराव**

हिंदुओं के मंदिर भी राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के अड्डे बन गये हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों के लिए।—**कम्युनिस्ट नेता ईएमएस नंबूदिरीपाद**

आतंकवादी न तो सिख हैं और न सिख परंपराओं के प्रति उनमें कोई सम्मान है। **—पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे**

मुझे एक सीट जीतने में कोई रुचि नहीं है। मैं पूरा प्रदेश जीतना चाहता हूं।—**डीएसपी के नेता कांशीराम**

हिंद महासागर का नाम बदलकर इसको 'मुस्लिम महासागर' कहना चाहिए। **—'पाकिस्तान टाइम्स' से**

हमारे अपने ही देश में इतनी समस्याएं हैं कि हमें सिख आतंकवादियों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है।—**वाइस आफ जर्मनी रेडियो से एक मुलाकात में जुनेजो**

एक देश के रूप में पाकिस्तान का अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं रहेगा।—**सिंध के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता गुलाम मुर्तजा सैयद**

हम लोगों ने सत्ता पर से एकाधिकार खतम करने का फैसला किया है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सत्ता छोड़ने जा रहे हैं।—**अफगानिस्तानी राष्ट्रपति डा० नजीबुल्लाह**

महिलाओं की शक्ति अपरंपार है। यदि वे एक बार ठान लें, तो पंजाब समस्या का समाधान अकेले ही कर सकती हैं।—**सांसद सुनील दत्त**

औरतें खुद अपना शोषण और अपमान कराती हैं।—**राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री अर्च**

राधा पॉकेट बुक्स

—की नयी पुस्तकें—

सुपर स्टार लेखक

परशुराम शर्मा

का नया उपन्यास

अपहरण

10/-

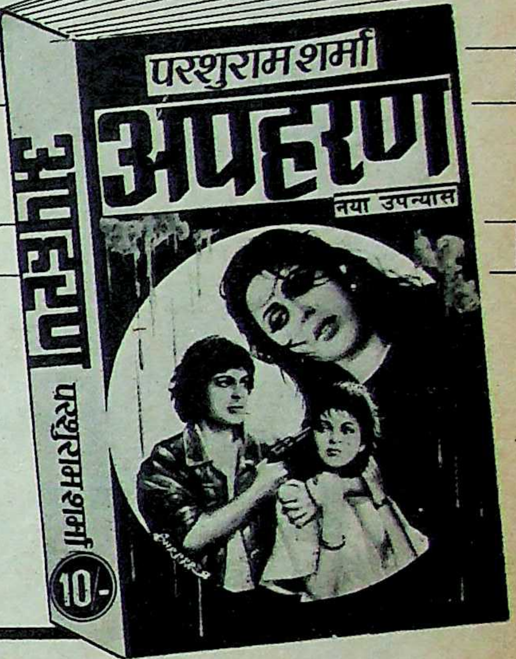
परशुराम शर्मा
अपहरण
नया उपन्यास
अपहरण
परशुराम शर्मा
10/-

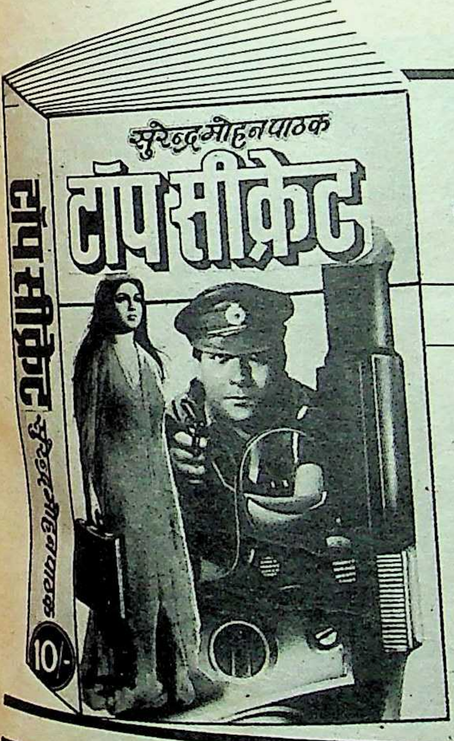
सुरेन्द्र मोहन पाठक
टॉप सीक्रेट
टॉप सीक्रेट
सुरेन्द्र मोहन पाठक
10/-

सुरेन्द्र मोहन पाठक

का 'सुनील सीरीज' का जासूसी उपन्यास

टॉप सीक्रेट

10/-

जनप्रिय लेखक

ओम प्रकाश शर्मा

का 'जगत सीरीज' का
नया जासूसी उपन्यास

हत्यारे का नाम नहीं होता

10/-

जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा
हत्यारे का नाम नहीं होता

भारत की
बहुचर्चित लेखक जोड़ी

धरम राकेश

का नया उपन्यास

कातिल चूड़ियाँ

6/-

धरम राकेश
कातिल चूड़ियां
6

राधा पॉकेट बुक्स

33, हरी नगर, मेरठ-250002 फोन : 22734, 21025

आरिफ की त्रासदी

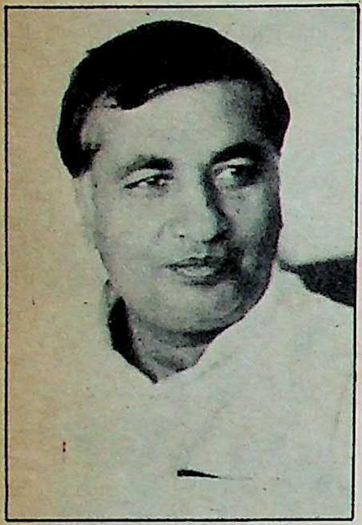

जनमोर्चा के संस्थापक सदस्य और तूफानी कार्यकर्ता आरिफ मोहम्मद खान आज कल कहां हैं? शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा संबंधी कानून में संशोधन का विरोध कर केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के कारण आरिफ न केवल देश-विदेश में चर्चा के विषय बन गये थे, अपितु उन्होंने सारे राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया था। जहां उस समय आरिफ का देश भर में स्वागत किया गया, वहीं मुस्लिम वर्ग ने उनके प्रति जबरदस्त आक्रोश का प्रदर्शन भी किया था।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के त्यागपत्र देने के काफी पूर्व आरिफ, प्रधानमंत्री विरोधी मोर्चे के अगुआ बन गये थे और जब सिंह अलग हुए, तो दोनों ने देशव्यापी दौरा भी किया।

बरेली की जनसभा में आरिफ की उपस्थिति पर मुस्लिम समुदाय ने इतना जबरदस्त हंगामा किया कि सिद्धांत और आदर्श की राजनीति के दावेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें फिर किसी सभा के मंच पर अपने साथ उपस्थित होने का अवसर नहीं दिया। पूर्व पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके बगलगीर बन गये।

आरिफ अभी जनमोर्चा में हैं, लेकिन इलाहाबाद में उनकी परछाईं भी देखने को नहीं मिली। राजा के पक्ष में विभिन्न दलों के नेताओं को प्रचार करने के लिए इलाहाबाद आमंत्रित किया गया, लेकिन आरिफ का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। प्रखर और स्पष्ट वक्ता, जनसभाओं में सम्मोहन पैदा करने की क्षमतावाले आदर्शवादी तथा निश्चय पर अडिग, आरिफ मोहम्मद खान जनमोर्चा में भी अछूत बन कर रह गये हैं। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के साथ इससे बड़ी और क्या त्रासदी होगी?

मुख्यमंत्री आवास में आग

आज राजनीति ही कुछ ऐसी हो गयी है कि उसमें बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के निजी जीवन में भी लोग ताक-झांक कर बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। वीर बहादुर सिंह अगर हर मंगलवार को हनुमान मंदिर माथा टेकने जाते हैं, तो कुछ लोगों को उसमें भी आपत्ति होती है। अपने गांव में अगर वह यज्ञ कराते हैं, तो राजनीतिक विरोधी कहने लगते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कुरसी बचाने के लिए यज्ञ करा रहे हैं।

भगवान भला करे ऐसे राजनीतिक विरोधियों का जो वीर बहादुर के सुख-दुख के मौकों पर उनके बारे में तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। इसी २७ मई को वीर बहादुर के साथ एक दुखद घटना घट गयी। उस रात्रि लगभग आठ बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आग लग गयी। यह आग वीर बहादुर के शयनकक्ष में लगे एयर कंडीशनर में 'शार्ट सर्किट' की वजह से लगी थी और देखते-ही-देखते शयनकक्ष, ड्रेसिंगरूम और डायनिंगरूम में रखा सारा सामान जल कर खाक हो गया। वीर बहादुर उस समय अपने कार्यालय में थे, जबकि पत्नी और बच्चे लान में बैठे थे।

वीर बहादुर का कहना है कि उनका और उनके परिवार का तमाम निजी सामान आग की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि उनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं बचे। इस हादसे पर जहां राज्यपाल से लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों और मित्रों ने वीर बहादुर से हमदर्दी जतायी, वहीं विपक्ष के कई नेता किस्से गढ़ कर सुनाने व मजे लेने से बाज नहीं आये। विपक्ष के एक नेता जनेश्वर मिश्र ने वीर बहादुर के पास पचास रुपए की आर्थिक सहायता भेजते हुए कहा, "इससे आप अपने पहनने के कपड़े सिलवा लीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि गांव में अग्निकांड के समय लोग कैसी परेशानी उठाते हैं।"

कुछ भी हो वीर बहादुर सिंह कहीं आरामदायक जगह जाने के बजाय तीन रातों तक वह अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे सोये—शिद्दत की गर्मी और शरीर जला देनेवाली लू के थपेड़ों के बीच इस बीच लोगों ने तरह-तरह की अफवाहें फैलायीं। किसी ने कहा कि इस अग्निकांड में कई महत्वपूर्ण फाइलें नष्ट हो गयी हैं। जनमोर्चा के एक नेता ने इस हादसे को चुनाव के साथ जोड़ते हुए कहा, "इलाहाबाद चुनाव के लिए राजीव गांधी ने जो रुपया भेजा था, वह गायब करने के लिए ही अग्निकांड का यह ड्रामा किया गया है।" एक नेता ने तो वीर बहादुर से इस्तीफे की मांग करते हुए यहां तक कह दिया, "जब मुख्यमंत्री का आवास ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की जनता सुरक्षित कैसे रहेगी?"

लेकिन संकट मोचन ने इस विपत्ति में भी अपने भक्त वीर बहादुर की मदद की। उनका परिवार जहां इस अग्निकांड से पूरी तरह सुरक्षित बच गया, वहीं आग की लपटों से शयनकक्ष में रखे उस तावीज को भी कोई क्षति नहीं पहुंची, जो एक पहुंचे हुए फकीर ने कभी वीर बहादुर को दी थी।

इस अग्निकांड से कुछ दिन पूर्व उक्त तावीज का तागा टूट गया था। वीर बहादुर ने इसे उतार कर शयनकक्ष में पीतल की घड़ी पर रख दिया था। आग से पीतल की घड़ी तो पिघल गयी, किंतु मोमिया कागज में लिपटे इस तावीज में धुआं तक नहीं लगा। वह जैसे का तैसा सुरक्षित बचा रहा। ■

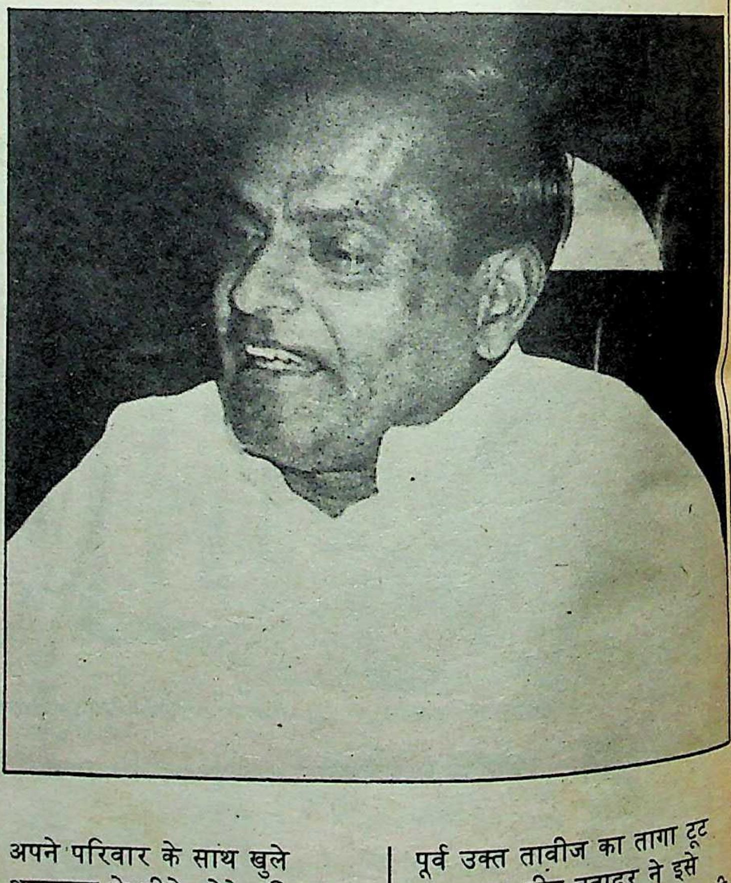

Sista's - 1495/88 Hin

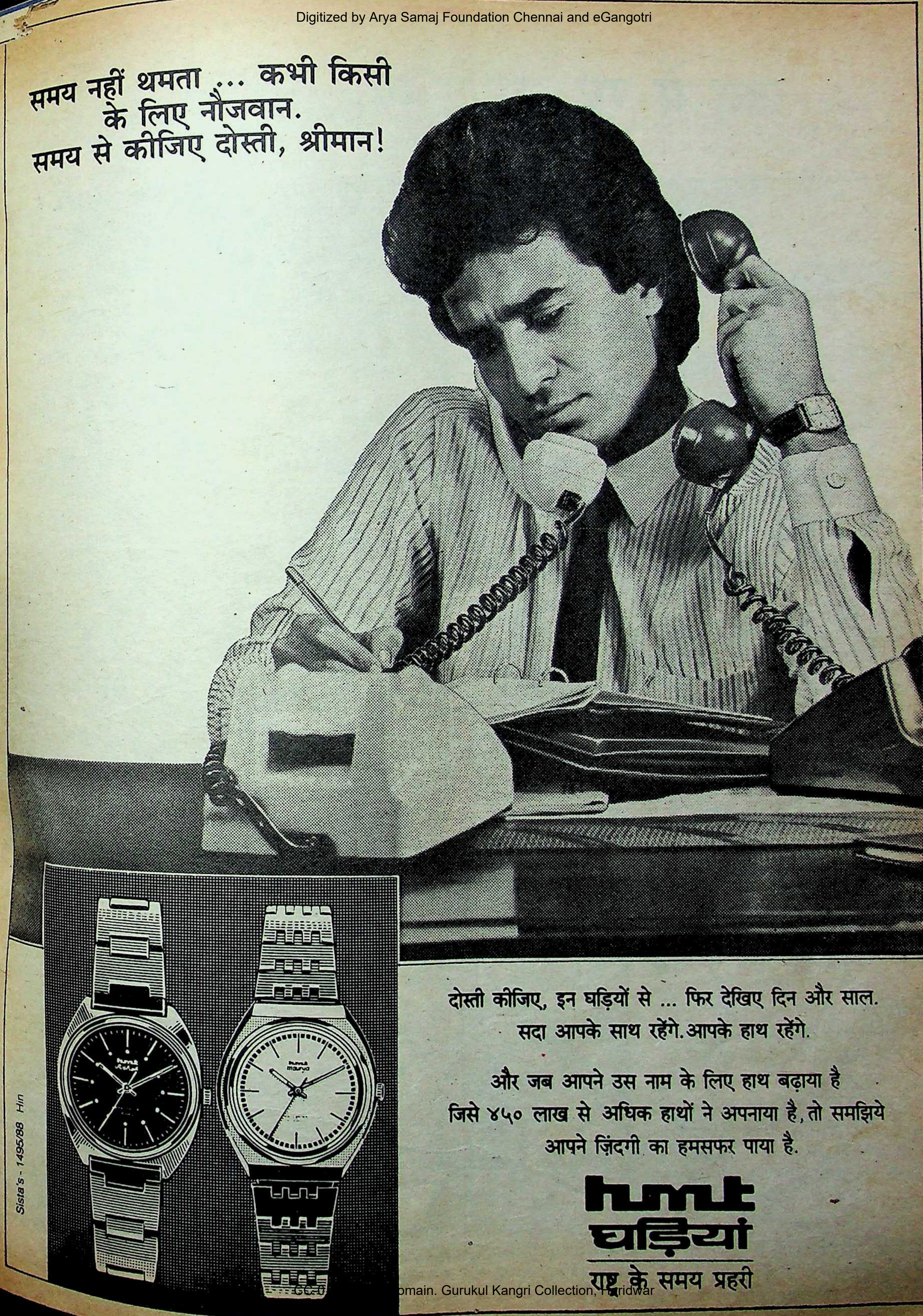

समय नहीं थमता ... कभी किसी
के लिए नौजवान.
समय से कीजिए दोस्ती, श्रीमान!

दोस्ती कीजिए, इन घड़ियों से ... फिर देखिए दिन और साल.
सदा आपके साथ रहेंगे. आपके हाथ रहेंगे.

और जब आपने उस नाम के लिए हाथ बढ़ाया है
जिसे ४५० लाख से अधिक हाथों ने अपनाया है, तो समझिये
आपने ज़िंदगी का हमसफर पाया है.

hmt
घड़ियां
राष्ट्र के समय प्रहरी

Sista's - 1495/88 Hin

राज कपूर

जग में रह जायेंगे प्यारे तेरे बोल

प्यार का पुजारी: 'जिस देश में गंगा बहती है' में राज कपूर

मनोरंजन सम्राट: 'धरम-करम' फिल्म में राज कपूर

जीवित मियक: सिम्मी और राज कपूर

दादा साहब फाल्के पुरस्कार बंबई से लेने दिल्ली आये राज कपूर बंबई लौटे, तो रात के अंतिम पहर में चुपचाप एकदम शांत। शो मैन और सपनों के सौदागर कहे जानेवाले राज कपूर का 'हिना' बनाने का सपना टूट चुका था और इस शो मैन का आखिरी शो २ जून, १९८८ को रात ९.२० पर सदा-सदा के लिए खतम हो गया। एक महीने की (२ मई से २ जून) लंबी बीमारी के बाद वह इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गये। इसे इत्तफाक ही कहा जायेगा कि लगभग इसी उम्र में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। राज कपूर को भी जब यह पुरस्कार मिला, तो ऐसे समय कि जब वह इस पुरस्कार को पाने के बाद उसे अच्छी तरह चूम भी नहीं सके।

१९३५ में केदार शर्मा के क्लेपर ब्वाय के रूप में फिल्मी कैरियर शुरू करनेवाले राज कपूर समय के साथ अपने को तराशते गये और

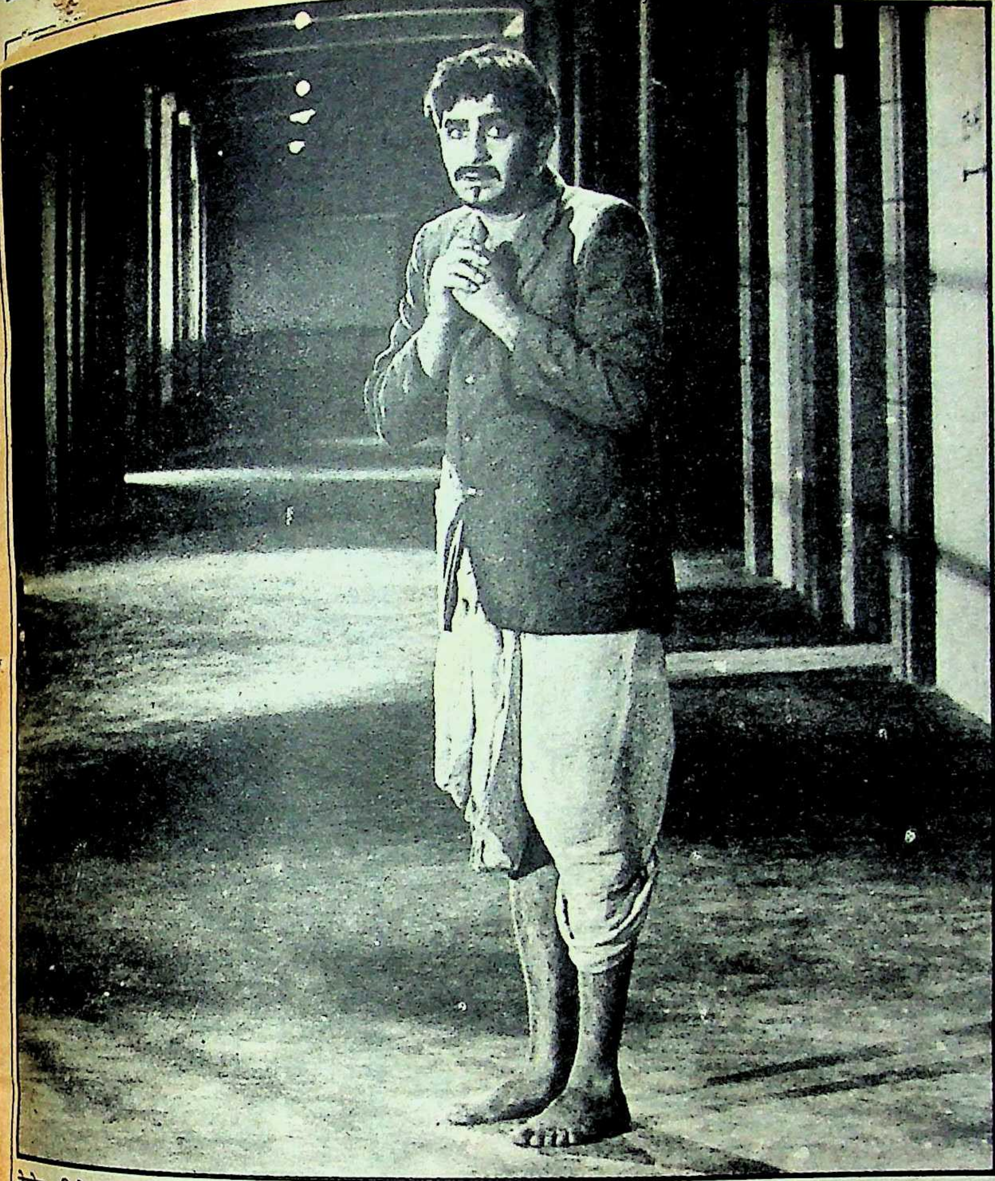

बेजोड़ अभिनेता: 'जागते रहो' में राज कपूर

एक दिन भारतीय सिनेमा के ऐसे लौह पुरुष बन गये, जिसकी मिसाल राज कपूर ही हैं—दूसरा कोई नहीं हो सकता। २४ वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म बनायी 'आग' (१९४८) जो भारतीय सिनेमा का एक स्तंभ कही जाती है। राज कपूर ने तकरीबन ६३ फिल्मों में अभिनय किया, १० फिल्मों का निर्देशन किया और एक फिल्म में गेस्ट स्टार रहे। वैसे ६८ फिल्मों में वह अभिनेता, निर्देशक या निर्माता रहे। राज कपूर की 'बूट पालिस', 'जागते रहो', 'संगम', 'श्री ४२०', 'अनाड़ी', 'जिस देश में गंगा बहती है', 'बाबी' और 'मेरा नाम जोकर' फिल्में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पा चुकी हैं। 'आवारा' फिल्म से राज कपूर मास्को में सबसे लोकप्रिय कलाकार बन गये।

राज कपूर हिंदी सिनेमा में इस बात के लिए अद्वितीय हैं कि वह सुपर स्टार भी रहे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल निर्देशक भी। राज कपूर के पहले भी हिंदी फिल्म में बहुमुखी प्रतिभाएं रही हैं, लेकिन राज कपूर की उपलब्धि इस माने में बड़ी है कि वह हिंदी सिनेमा के पहले 'आधुनिक युवा' थे। अभिनय, निर्देशन और निर्माण में उन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया। उनके पहले के किसी भी फिल्मकार में सिनेमा के हर विभाग की समझ नहीं थी जो राज कपूर के पास थी। फिल्म निर्माण के हर सशक्त पक्ष पर उनकी पकड़ के कारण ही उनकी फिल्मों की एक पहचान होती थी जिसे 'राज कपूर स्पर्श' कहा जाता था।

—दिनेश दीनू

दोस्त: राज कपूर और दिलीप कुमार

संरक्षक व मार्गदर्शक: 'प्रेम रोग' फिल्म के एक सेट पर राज कपूर ऋषि कपूर

लड़कियों ने बाजी मारी

दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (१२वीं कक्षा) में बैठे कुल ५४४४१ विद्यार्थियों में ८७.४ प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुई, जबकि उत्तीर्ण हुए लड़कों का प्रतिशत ७८.७ था। गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में लड़कियां, लड़कों से आगे रहीं। गणित में इस वर्ष १०० में से १०० अंक प्राप्त करनेवाले २३ विद्यार्थियों में १७ लड़के हैं और छह लड़कियां। रसायन विज्ञान में दो छात्रों और दो छात्राओं ने सौ में से ९९-९९ अंक प्राप्त किये। इंजीनियरिंग डिजायन में दीप्ति शर्मा ने ९८ प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

१६ जून को आठ राज्यों में होने वाले ७ संसदीय और ११ विधान सभा उपचुनावों में सर्वाधिक ६८ प्रत्याशी इलाहाबाद संसदीय सीट से लड़ रहे हैं, जहां अमिताभ बच्चन के बजाय सुनील शास्त्री वीपी सिंह का मुकाबला करेंगे।

बंगला देश को चूहों से निजात दिलाने के लिए वहां की सरकार ने 'चूहे की पूंछ लाओ, ५० पैसे ले जाओ' कार्यक्रम शुरू किया था जिसके तहत वहां के लोगों ने ४७ लाख चूहों को मारकर उनकी पूंछे सरकारी खजाने में जमा करा दीं और पुरस्कार प्राप्त कर लिया। चूहों को मारने का अभियान वहां युद्ध स्तर पर जारी है। सरकारी अनुमान के अनुसार बंगला देश में इस समय तीस करोड़ चूहे हैं जो १६० लाख टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष चट कर जाते हैं।

जापानी दीर्घजीवन के लिए सोने का वर्क खा रहे हैं। गत वर्ष वहां सप्लाई हुए २००५ टन सोने में से आठ किलो सोना जापानियों के पेट में चला गया।

दुनिया में प्रति वर्ष ११३८ टन सोना आभूषण बनाने में और २४४ टन सोना औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।

पश्चिमी देशों में जितनी मौतें हेरोइन या अन्य मादक पदार्थों की वजह से होती हैं, उनसे बीस गुना अधिक मौतें शराब पीने से होती हैं।

ब्रिटेन के रायल कालेज आफ फिजिक्स ने शराब से होनेवाले हादसों का अध्ययन करके कुछ अन्य चौंकानेवाले तथ्य जगजाहिर किये हैं। ब्रिटेन में आग से हुई मौतों, सड़क दुर्घटनाओं, घरेलू दुर्घटनाओं और डूबने से हुई मौतों में क्रमशः ५२, ४५, ३३ व ३० प्रतिशत मौतों के लिए शराब जिम्मेदार रही है और वहां शराबी हर आठ मिनट में औसतन एक हिंसक वारदात कर रहे हैं। दूसरों पर हमले की ब्रिटेन में गत वर्ष जितनी भी घटनाएं हुईं, उनमें ७५ प्रतिशत हमलावरों ने शराब पी रखी थी।

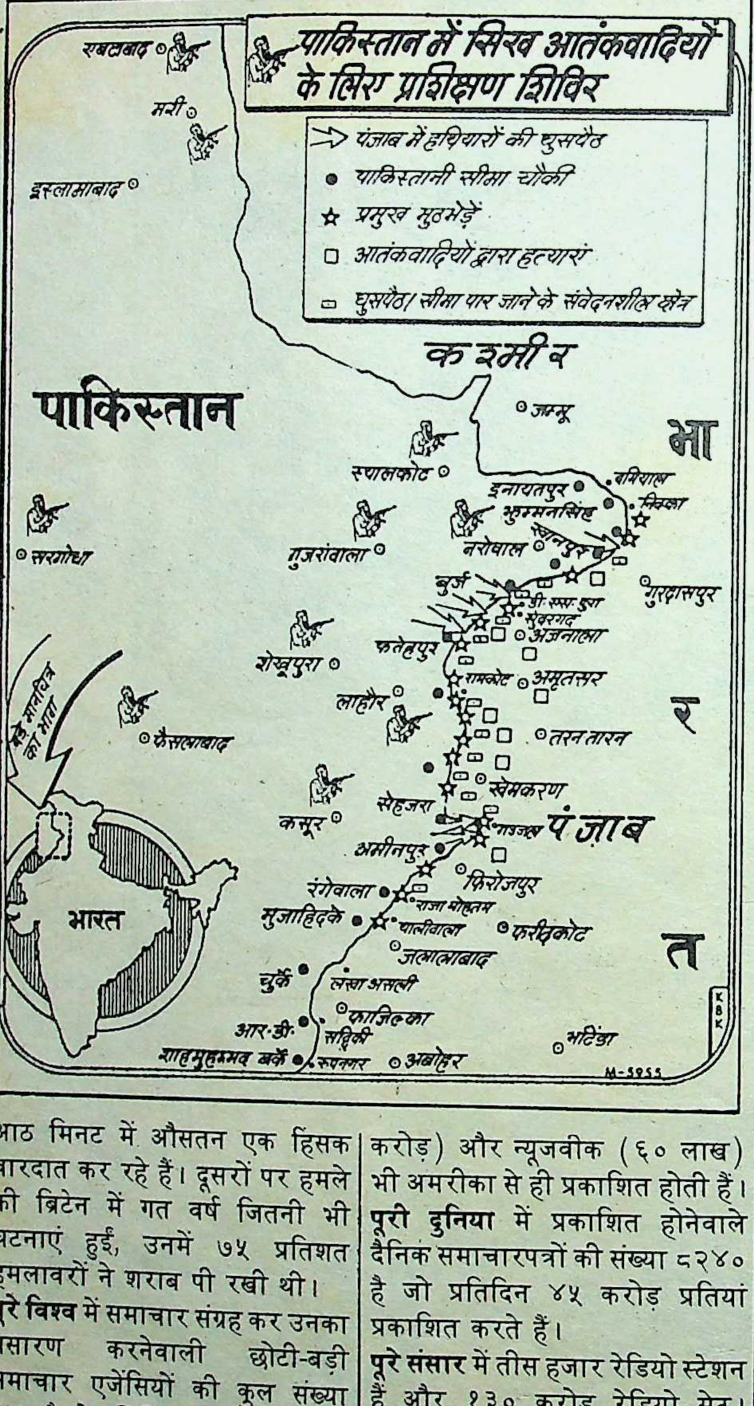
पाकिस्तान में सिख आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर
पंजाब में हथियारों की घुसपैठ
● पाकिस्तानी सीमा चौकी
☆ प्रमुख मुठभेड़ें
□ आतंकवादियों द्वारा हत्याएं
▭ घुसपैठ/सीमा पार जाने के संवेदनशील क्षेत्र
रबटाबाद
मरी
इस्लामाबाद
कश्मीर
पाकिस्तान
जम्मू
भारत
स्यालकोट
इनायतपुर
बमियाल
मिस्का
भुम्मनसिंह
नरोवाल
गुरदासपुर
सरगोधा
गुजरांवाला
बुर्ज
डी.एस. पुरा
सुंदरगढ़
अजनाला
फतेहपुर
शेखूपुरा
रामकोट
अमृतसर
लाहौर
तरनतारन
फैसलाबाद
खेमकरण
सेहजरा
कसूर
पंजाब
अमीनपुर
फिरोजपुर
रंगेवाला
राजा मोहतम
मुजाहिदके
फरीदकोट
जलालाबाद
चुर्के
लखा असली
फाजिल्का
आर.डी.
भटिंडा
शाहमुहम्मद बर्के
रूपनगर
अबोहर
बड़े मानचित्र का भाग
भारत
KBK
M-5955

पूरे विश्व में समाचार संग्रह कर उनका प्रसारण करनेवाली छोटी-बड़ी समाचार एजेंसियों की कुल संख्या १४० है जो प्रतिदिन समाचारों के चार करोड़ शब्द प्रसारित करती हैं। अमरीका की एपी और यूपीआई समाचार एजेंसी क्रमशः १.७० और १.१० करोड़ शब्दों में समाचार प्रसारित करती हैं अर्थात पूरे संसार में प्रसारित कुल समाचारों के ७० प्रतिशत समाचारों पर अमरीका का नियंत्रण है।

सर्वाधिक प्रसार संख्यावाली तीन प्रसिद्ध पत्रिकाएं रीडर्स डायजेस्ट (२.८० करोड़) टाइम (१.२० करोड़) और न्यूजवीक (६० लाख) भी अमरीका से ही प्रकाशित होती हैं।

पूरी दुनिया में प्रकाशित होनेवाले दैनिक समाचारपत्रों की संख्या ८२४० है जो प्रतिदिन ४५ करोड़ प्रतियां प्रकाशित करते हैं।

पूरे संसार में तीस हजार रेडियो स्टेशन हैं और १३० करोड़ रेडियो सेट। विश्वभर के कुल टीवी स्टेशनों की संख्या ३३ हजार और टीवी सेटों की संख्या ५० करोड़ है।

प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में सात लाख नयी पुस्तकों की आठ सौ करोड़ प्रतियां प्रकाशित होती हैं।

पूरी दुनिया में ढाई लाख सिनेमाहाल हैं, जिनमें तीन शो के हिसाब से ७ करोड़ २० लाख दर्शक प्रतिदिन फिल्म देख सकते हैं।

दुनिया भर के कंप्यूटरों में जितनी जानकारियां संग्रहित हैं, उनका ९० प्रतिशत अमरीका के पास है।

पूर्वी जर्मनी के उल्फ टिमरमैन ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैक ऐंड फील्ड प्रतियोगिता में २३.०६ मीटर दूर तक गोला फेंककर इटली के अलमांद्रो आंद्रेई के १९८७ में स्थापित २२.९१ मीटर तक गोला फेंकने के विश्व रिकार्ड को तोड़ दिया है।

चीन में खाद्यान्न का जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन पांच टन है, वहीं भारत में यह मात्र १.७ टन है।

आतंकवादियों के भय से स्वर्ण मंदिर वीरान हो गया था, लेकिन १८ मई को स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों के सफाये के बाद २३ मई को जब स्वर्ण मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, तो पहले ही दिन १० से १५ हजार के बीच श्रद्धालुओं ने हरमंदिर साहब में मत्था टेका। इतने श्रद्धालु तो इस वर्ष वैशाखी पर भी स्वर्ण मंदिर नहीं पहुंचे थे।

यदि किसी लापता सरकारी कर्मचारी का लगातार तीन सालों तक पता न चले, तभी सरकार उसे मृत मानती है और लापता होने की तिथि से तीन साल बाद ही उस कर्मचारी के परिवार को वेतन व बकाया रकम मिल सकती है।

अब मनिआर्डर भेजते समय सामान्य मनिआर्डर शुल्क के अतिरिक्त पांच रुपए का भुगतान करने पर आपके द्वारा प्रेषित धन २४ से ७२ घंटे के अंदर गंतव्य स्थल तक पहुंच जायेगा। भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने ऐसी मनिआर्डर सेवा शुरू की है।

राष्ट्रपति ने १९ मई को एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर बेनामी संपत्ति के मालिकों के अधिकारों पर रोक लगा दी है। इससे बेनामी किस्म के किसी सौदे को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। संपत्ति का जहां बेनामी हस्तांतरण हुआ है, वहां असली मालिक वह माना जायेगा, जिसे संपत्ति दी गयी है। जम्मू और कश्मीर के अलावा यह अध्यादेश पूरे देश में लागू होगा।

एड्स रोग के इलाज के लिए अभी तक २५ टीके ईजाद हुए, लेकिन ए जेड टी अर्थात जीडोवुडाइन दवा ही कुछ फायदेमंद साबित हुई है। यह दवा इतनी महंगी है कि एक मरीज पर इसका खर्च डेढ़ लाख रुपए बैठता है। फिलहाल ३७ देशों में १९ हजार रोगी यह दवा ले रहे हैं। वैसे यह रोग विश्व के १३३ देशों में फैल चुका है।

—संयोजन : विनोद मिश्र

इलाहाबाद चुनाव

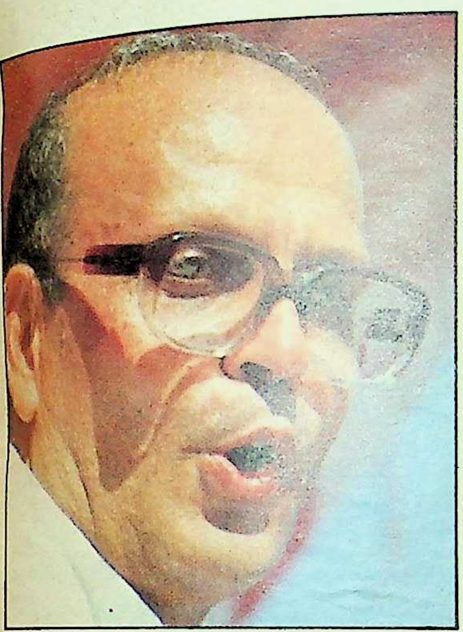

वीर बहादुर की हाथ की सफाई का डर : राजा

छाया : मनमोहन शर्मा

पिता की छवि और सत्ता का सहारा : सुनील शास्त्री

जात पांत के गणित पर भरोसा : कांशी राम

छाया : वसीमुल हक

वीपी सिंह का कितना जोर ?
अमिताभ ने मैदान क्यों छोड़ा ?
सुनील शास्त्री मैदान में क्यों ?

अंतिम पल तक कांग्रेस-इ ने यह रहस्य बनाये रखा कि इलाहाबाद उपचुनाव में उसका अपना प्रत्याशी कौन होगा। साथ ही यह अफवाह भी जारी रखी कि अमिताभ बच्चन ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर यह रहस्य क्यों बनाये रखा ? क्या अमिताभ बच्चन को न खड़ा करके राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से अपना दामन छुड़ा लिया है ? अमिताभ को मैदान से हटाने के पीछे क्या कारण थे : क्या कांग्रेस-इ का यह कहना झूठ था कि नामांकन के समय अमिताभ बच्चन विदेश में इलाज करवा रहे थे ? सुनील शास्त्री को मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस-इ की रणनीति क्या थी ? कांग्रेस-इ इस उपचुनाव में अंधाधुंध अपनी शक्ति लगा रही है और बहुजन पार्टी के अध्यक्ष कांशी राम भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि वीपी सिंह धन शक्ति के बजाय जन शक्ति के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीपी सिंह की जीत के आसार क्या हैं ? इस चुनाव में किसका क्या दांव पर लगा है ? 'माया' की टीम और विशेषज्ञों द्वारा इस रोमांचक उपचुनाव का विश्लेषण :

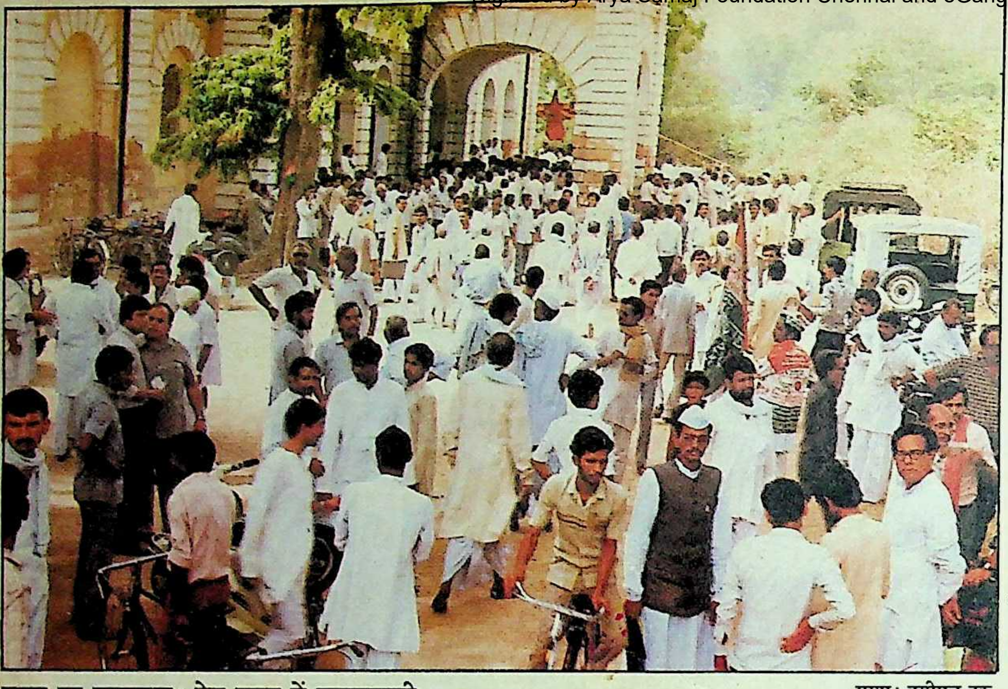

राजा का मुख्यालय : ऐश महल में गहमागहमी

छाया : वसीमुल हक

छाया : मुकेश सहगल

पांचवां बेटा : शास्त्रीजी को माल्यार्पण करते वीपी सिंह

वीपी सिंह का कितना जोर ?

इलाहाबाद में अशोक रोड पर उखड़े पलस्तर से झांकती बूढ़ी ईंटों की, अपने नाम (ऐश महल) का मजाक उड़ाती, एक कोठी। इसके अहाते और बाहर सड़क पर इक्के-दुक्के चौपहिया और कतार में ढेर सारे दो पहिया वाहन खड़े हैं, जिन पर चरखे की जगह लाल गोला लगे तिरंगे झंडे की जगह अब गुलाबी रंग की पताकाएं लहरा रही हैं। सफेद कुरते पायजामे पहने और सिर तथा कनपटियों को गाढ़े गमछे से बांधे अभियान पर निकलने के लिए तत्पर कार्यकर्ता अपने नेता के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके नेता हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उनकी नजर में 'राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर हैं' और विरोधियों की नजर में 'राजा है न रंक है, सीआईए एजेंट है।'

इलाहाबाद के सर्किट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और बीपीसीएल गेस्ट हाउस के सामने चमचमाती कारों-जीपों की भीड़। सफेद-बुर्राक कुरते-पायजामे में कुछ नवोदित नेता मंडरा रहे हैं। जब भी कोई जमा हुआ नेता वातानुकूलित कमरों में बैठे बड़े नेता से मिल कर बाहर निकलता है, तो नवोदित नेता उससे शिकायत करते हैं— न गाड़ी न घोड़ा, का करी। जमा हुआ नेता पिंड छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और उड़न-छू हो जाता है। ये विश्रामगृह कांग्रेस-इ के चुनाव अभियान के शाखा कार्यालय हैं, जहां सत्ता का वैभव आसानी से देखा जा सकता है और चुनाव की असली रणनीति यहीं तय होती है। वैसे कांग्रेस-इ का केंद्रीय चुनाव कार्यालय महिला विद्यापीठ है।

ताऊसी होटल। जनमोर्चा और कांग्रेसी खेमे में बेचैनी पैदा करनेवाले बहुजन समाज पार्टी के जनक कांशीराम इसी होटल में ५ कमरे लेकर ठहरे हुए हैं। दीवारों की लिखावट और जातीय आंकड़ों के हिसाब से देखा जाये, तो ऐसा लगता है कि वीपी सिंह और सुनील शास्त्री बेकार में खड़े हैं। कांशीराम सड़कों पर भीड़ के साथ निकलते हैं और 'एक वोट एक नोट' बटोरने का अभियान छेड़े हुए हैं। उनका चुनाव कार्यालय लोकसेवा आयोग के पास एक टुटहे से मकान में है, जहां गैरराजनीतिक चेहरेवाले नौजवान बैठे रहते हैं। जिनको कम खबर होती है कि उनके 'साहिब' का किस समय क्या कार्यक्रम है?

ये तीन खेमे, जो उस महायुद्ध में एक दूसरे को पछाड़ने में तुले हैं, जिस पर देश-विदेश की आंखें टिकी हुई हैं। १९५२ से १९८४ तक इलाहाबाद का सांसद बनने के लिए दस बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसी उत्सुकता-उत्तेजना कभी नहीं रही, जैसी १६ जून, १९८८ को होने वाले उपचुनाव को लेकर है। २३ मई को आखिरी क्षणों तक बेताब इंतजार के बाद जब अमिताभ बच्चन नहीं पहुंचे, तो यह लगनें लगा कि राजीव गांधी ने इस उपचुनाव से जुड़ी उत्तेजना के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। ऐसा भी लगा था कि वीपी सिंह के लिए जीत का सेहरा बांधने का काम बिलकुल आसान कर दिया है। जिस समय वीपी सिंह पर्चा दाखिल करके अपने 'ऐश महल' में पहुंचे थे, तो ऐसा माहौल था, जैसे चुनाव-परिणाम आ गया हो और विजयोत्सव मनाया जा रहा हो। 'ऐश महल' में शाम को नगाड़े भी बजे। लेकिन पिछले पंद्रह दिनों में चुनाव जिस तरह गरमाया है, उससे यह लगने लगा है कि इस उपचुनाव में हार-जीत का फैसला उतना आसान नहीं है, जितना शुरू में लग रहा था। यह अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि एक ओर वीपी सिंह के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, तो दूसरी ओर राजीव गांधी की लोकप्रियता दांव पर लगी है। यदि राजा जीतते हैं, तो पूरा विपक्ष इसे राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ जनादेश के रूप में प्रचारित करेगा और कांग्रेसियों का मोहभंग होगा। वे सोचने लगेंगे कि भविष्य में राजीव गांधी उनको जिता कर नहीं ला सकते।

ऐतिहासिक चुनाव : इसी कारण इलाहाबाद के इस उपचुनाव ने ऐतिहासिक रूप अख्तियार कर लिया है। दो-दो प्रधानमंत्री देनेवाली इलाहाबाद सीट पर केवल दो बार विपक्ष की जीत हुई है, बाकी आठ बार कांग्रेसी प्रत्याशी ही यहां से जीते हैं (देखिए चुनाव का इतिहास)। कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहां से १९८० में चुनाव जीत चुके हैं। गोरखपुर से विधायक और राज्य के पूर्व ऊर्जामंत्री सुनील शास्त्री यहां से पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री १९५७ और १९६२ में तथा उनके भाई और अब केंद्रीय राज्यमंत्री हरिकृष्ण शास्त्री १९६७ में यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस समय ८,४३,७७५ मतदाता हैं। १९८४ के मुकाबले

मैं अपने पिता का बाकी काम पूरा करूंगा : सुनील शास्त्री

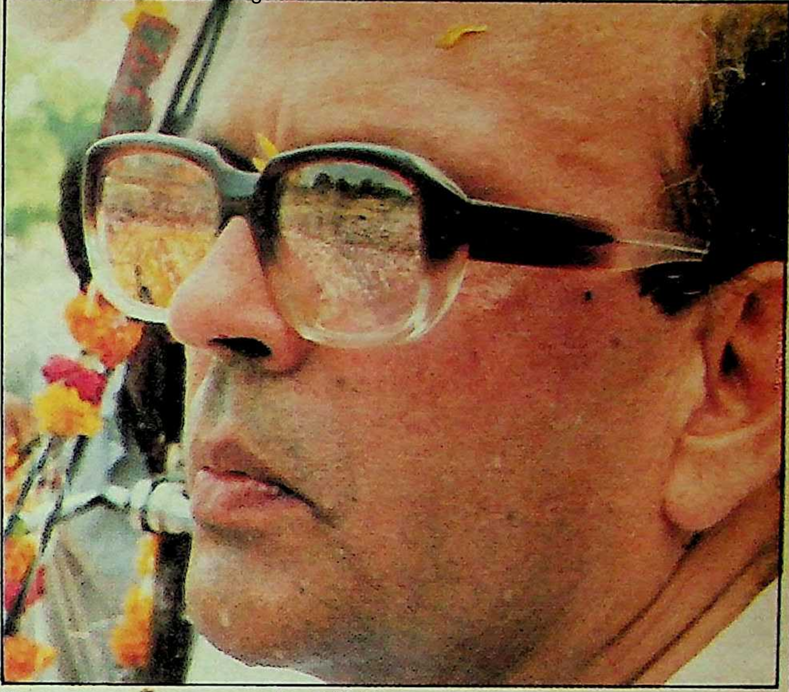

मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं : वीपी सिंह

इस बार ६७२५६ नये मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में पांच निर्वाचन क्षेत्र हैं— शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, मेजा, करछना और बारा। पहले दो क्षेत्र शहरी और शेष तीन ग्रामीण हैं। यहां तीन मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच मुकाबला है– वीपी सिंह, सुनील शास्त्री और कांशीराम। वीपी सिंह वैसे तो निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें संयुक्त विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। यह उनका दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव उन्होंने १९८४ में लोकसभा के लिए जांजगीर (मप्र) से लड़ा था, जहां उनकी जमानत जब्त हुई थी।

राजनीतिक झुकाव : इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पांच विधायकों में से तीन विधायक विपक्ष के हैं और दो कांग्रेस के। ९ ब्लाक प्रमुखों में से ५ वीपी सिंह के साथ हैं। वीपी सिंह ने पिछले एक साल से रक्षा सौदों में दलाली और राजनीति में धन की भूमिका के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। सारे देश में वह अलख जगाते घूमते रहे हैं। इस राष्ट्रीय छवि का लाभ उनको मिलेगा। वह अपने भाषणों और साक्षात्कारों में कहते रहे थे कि अमिताभ बच्चन कांग्रेस-इ का पर्याय बन गये हैं। लोककथाओं का संदर्भ देते हुए वह यह भी कहते थे कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे तोते हैं, जिसमें राजीव गांधी की जान है। अतः कुल मिलाकर उन्होंने अपना निशाना अमिताभ बच्चन को बना रखा था। वह राजीव गांधी को चुनौती दे रहे थे कि वह अमिताभ को खड़ा करके देखें। अब जबकि अमिताभ चुनाव में नहीं उतरे हैं, तो इसे राजा की नैतिक जीत माना जा रहा है। इससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। यह बात दूसरी है कि अमिताभ को न खड़ा करके राजीव गांधी ने राजा के आक्रमण को थोड़ा भोथरा कर दिया है। अब वह वे बातें उतनी ताकत से नहीं कह सकते, जो बातें अमिताभ के खड़े होने पर कह सकते थे।

नया प्रयोग : राजा ने इस उपचुनाव में एक नया प्रयोग करने की घोषणा की थी। इसके तहत उन्हें कोई बैनर, पोस्टर, दीवार-लेखन नहीं करना था और केवल दुपहिया वाहनों का ही प्रयोग करना था। इस चिलचिलाती धूप और भीषण लू में इस तरीके से प्रचार करना कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक कठिन था। लगभग दस दिन तक राजा अपनी इस नीति पर ही चले। बाद में उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया और जनमोर्चा के लोगों कें अतिरिक्त बाकी लोगों को कार-जीप आदि का इस्तेमाल करने और प्रचार-दरवाजे आदि बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन वे न के बराबर हैं। इससे ऐसा मुगालता होता है, जैसे वीपी सिंह का कोई जोर ही न हो। जबकि कांग्रेस-इ के झंडे-बैनरों से क्षेत्र अटा-पटा है और दीवारों पर सुनील शास्त्री और कांशीराम के नारों की छटा है। कांग्रेस-इ ने लगभग सवा सौ गाड़ियां प्रचार कार्य में लगा रखी हैं। दर्जनों मंत्री, सांसद, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष इलाहाबाद में डेरा डाले पड़े हैं। स्वयं मुख्यमंत्री का एक पांव लखनऊ में है, तो दूसरा इलाहाबाद में। बताया जाता है कि ४ जून को मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा के लिए विदा करने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको इलाहाबाद नहीं छोड़ना है। जहां तक पैसे का सवाल है, कांग्रेस-इ के पास कोई कमी नहीं। कांग्रेस के खजांची सीताराम केसरी ने भी अपना खजाना खोल रखा है और मुख्यमंत्री ने भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रखी है। प्रेक्षकों का अनुमान है कि कांग्रेस-इ लगभग एक करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। दूसरी ओर कांशीराम ने दीवारों पर नारे लिखने के लिए लगभग ३०० लोगों को लगा रखा है।

जातीय समीकरण : उपचुनावों में अकसर मतदाता का रुख सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है और चुनाव में स्थानीय मुद्दे प्रबल होते हैं। पर वीपी सिंह के कारण यह उपचुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना था। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आता जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर संकीर्णता के हावी होने की आशंका होने लगी है। जातीय आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कांशीराम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वह खुले आम भाषणों में और अपने 'इलाहाबाद उपचुनाव बुलेटिन' में लिख रहे हैं कि जब 'पंद्रह का एक वोट हमें नहीं मिलता, तो पचासी का वोट भी उन्हें नहीं मिलना चाहिए।' कांशीराम के गणित के अनुसार ८५ प्रतिशत हरिजन और पिछड़ी जातियां हैं, जबकि १५ प्रतिशत सवर्ण हैं। ८५ प्रतिशत वोट वह अपने लिए पक्का मान रहे हैं।

नयी जानकारी के अनुसार इलाहाबाद में लगभग १ लाख ९१ हजार हरिजन, ८२ हजार यादव, ३६ हजार कुरमी, १ लाख ३८ हजार ब्राह्मण, ५६ हजार ठाकुर, ८५ हजार मुस्लिम, ३० हजार बंगाली, १५ हजार पंजाबी, ८ हजार सिख, ४० हजार जायसवाल, ५ हजार ईसाई, ६० हजार कायस्थ तथा शेष अन्य जातियां हैं।

जातिगत आधार पर इलाहाबाद में कभी जीत-हार का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जातीय समीकरण काम नहीं करता। कांशीराम दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण-ठाकुर-बनियों के अतिरिक्त सारे वोट उनको ही मिलेंगे। उनके समर्थकों ने एक भड़काऊ नारा भी दिया था—'ठाकुर बांभन बनिया चोर, बाकी सब हैं डीएस-फोर।' लेकिन कांशीराम इस नारे को नहीं मानते। कांशीराम ने पिछले दो-तीन महीनों से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं की हैं। इन जनसभाओं में भीड़ भी काफी रही है। लेकिन

जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा होना दूसरी बात है और उस भीड़ को मतदाताओं में परिवर्तित करना दूसरी। कांशीराम के पास कोई पार्टी-ढांचा नहीं है और न ही कोई जाना-माना स्थानीय नेता उनके साथ है। स्थानीय प्रभावशाली, साधन संपन्न और दबंग कार्यकर्ता ही मतदाताओं को निकाल कर मतदान केंद्रों तक लाते हैं। ऐसी स्थिति कांशीराम के साथ नहीं है।

चायल से कांग्रेस-इ सांसद बीएल शैलेश तो यह भी कहते हैं, ''कांशीराम अपने को जिस जाति का बताते हैं, उस जाति के वह नहीं हैं।'' रोपड़ (पंजाब) के रहनेवाले कांशीराम का दावा है कि उनका काम 'लीडरशिप' पैदा करना है। वह इस बात को कतई नहीं मानते कि कांग्रेस ने हरिजनों के लिए कुछ किया है। आरक्षण की नीति की आलोचना करते हुए वह कहते हैं कि इस नीति से कांग्रेस ने अपने 'चमचे' पैदा किये हैं। उनका मानना है कि जगजीवन राम कभी हरिजनों के नेता नहीं रहे। ''वह कांग्रेस की कठपुतली थे।''

कांशीराम की दहशत का कारण है बिजनौर और हरिद्वार लोकसभायी उपचुनावों में उनकी पार्टी का शानदार प्रदर्शन। १९८५ में बिजनौर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी १.२५ लाख वोट पाकर तीसरे स्थान पर और १९८७ में हरिद्वार उपचुनाव में १.२५ लाख प्राप्त करके दूसरे स्थान पर थी। हो सकता है कांशीराम के आह्वान पर हरिजन उन्हें वोट दे दें, लेकिन गांवों में हरिजन शुद्ध जातीय आधार पर वोट देने की हिम्मत शायद ही जुटा पायें। अन्य जातियों से उनके आर्थिक तार जुड़े हैं और उन्हीं के बीच उन्हें गुजर-बसर करनी है, इसलिए गांव की हवा के खिलाफ वे शायद ही मतदान करें। फिर शहर के बजाय गांवों में हरिजन मतदाताओं की संख्या अधिक है। शहर में लगभग ५२ हजार हरिजन मतदाता हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख से ऊपर हरिजन मतदाता हैं।

कांग्रेस-इ की रणनीति: कांग्रेस-इ पिछले चुनावों में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर वोट मांगती रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस उपचुनाव में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कोई हवाला नहीं। इस उपचुनाव में २२ साल बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जा रहा है। शास्त्रीजी के प्रति पूजा भाव है और उन्हीं की विरासत को कांग्रेस ने मुख्य आधार बना रखा है। जगह-जगह बजने वाले कैसटों में लड़ाई के समय दिये गये शास्त्रीजी के नारे 'जयजवान जय किसान' को प्रचार-गीत का आधार बनाया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का विश्वास है कि जनता विकास के लिए वोट देती है और कांग्रेस विकास करने में लगी है। उनका कहना है कि उन्होंने ८० करोड़ रुपए इलाहाबाद के लिए मंजूर किये हैं, जिनमें ५५ करोड़ रुपए मुहैया करवा दिये गये हैं। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि राजा ने इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं किया है। ''वह देशद्रोही हैं, विश्वासघाती हैं और इलाहाबाद के लिए कलंक हैं।''

जहां तक कांग्रेस-इ के स्थानीय ढांचे का सवाल है, अमिताभ बच्चन को लेकर उसमें जो तगड़ा विरोध था, वह सुनील शास्त्री को प्रत्याशी बनाने के बाद लगभग समाप्त हो गया है। अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुहिम छेड़नेवालों में पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी सबसे आगे थे। अब उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अब भी उनके विरोधी यह प्रचार कर रहे हैं कि वह ऊपर से सक्रिय जरूर दिखायी देते हैं, लेकिन अंदर से निष्क्रिय हैं। जबकि अशोक वाजपेयी के समर्थक इस बात को नहीं मानते। उनके समर्थकों का कहना है

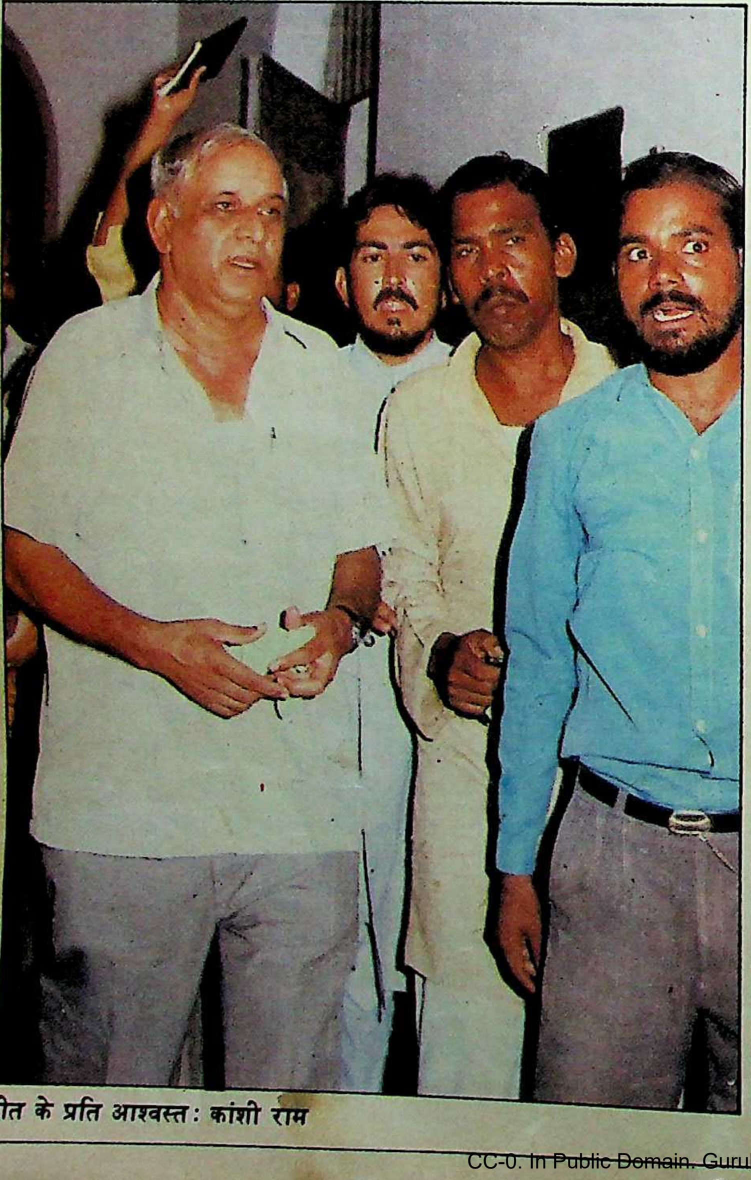

जीत के प्रति आश्वस्त: कांशी राम

जनमोर्चामय एक प्रचारक

वीपी सिंह के चुनाव निशान का प्रचार

छाया : वसीमुल हक

कि अशोक वाजपेयी शहर उत्तरी में अपनी पूरी ताकत लगायेंगे ताकि वह यह परख सकें कि उनका आधार कितना है। शहर उत्तरी में कांग्रेस के टिकट पर लड़कर हारी सरोज दुबे इस समय राजा के पाले में हैं। वहां से जीतने वाले विधायक अनुग्रह नारायण सिंह तो राजा के लिए जी-जान लगा ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अशोक वाजपेयी का सक्रिय होना स्वाभाविक लगता है। यह उल्लेखनीय है कि शहर उत्तरी में अमिताभ बच्चन सर्वाधिक मतों (६३,९१३) से जीते थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो यह सीट लोकदल के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह ने जीत ली थी। जाहिर है अशोक वाजपेयी ने अपना ज़ौहर दिखाया होगा। हां, स्थानीय नेताओं को इस बात का गम जरूर है कि यहां चुनाव की लगाम बाहर से आये दिग्गज नेताओं के हाथों में है। इसलिए अगर चुनाव जीता, तो श्रेय स्थानीय नेताओं के बजाय बाहर के नेताओं को मिलेगा। लेकिन चुनाव प्रभारी गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित इस बात को नहीं मानते, "सभी कांग्रेसी भेदभाव भुला कर एक हैं।" सुनील शास्त्री के बड़े भाई और केंद्रीय राज्यमंत्री हरिकृष्ण शास्त्री को भी पूरी उम्मीद है कि सभी कांग्रेसी जुटे हुए हैं और 'बाबूजी' (शास्त्रीजी) के प्रति लोगों में श्रद्धा है, इसलिए उन्हें "सुनील की जीत में कोई संदेह नहीं।" रात में विपक्षी कार्यकर्ताओं की तोड़-फोड़ करने में लगे राज्यसभा सांसद एसपी मिश्रा उर्फ 'बाबा मिश्रा' का कहना है कि सुनील शास्त्री को खड़ा करके राजीव गांधी ने राजा के प्रचार की हवा निकाल दी है। लेकिन सुनील शास्त्री किसी भी विरोधी को कमजोर नहीं मानते, "मैं हर प्रत्याशी को गंभीरता से ले रहा हूं।"

बहुगुणा का रुख : यद्यपि वीपी सिंह विपक्ष के सर्वसम्मत प्रत्याशी हैं, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा के रुख के बारे में अब भी प्रेक्षक एक मत नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुगुणा १९८४ की असामान्य परिस्थितियों में बच्चन से हारे थे, लेकिन उस आंधी में भी उन्होंने १,०९,६६६ मत प्राप्त किये थे जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। यहां जितने कर्मठ और दबंग कार्यकर्ता बहुगुणा के पास हैं, उतने किसी के पास नहीं। बहुगुणा के अनुयायी चायल के प्रभावशाली पूर्व सांसद और हरिजन नेता रामनिहोर राकेश के वीपी सिंह से मतभेद हैं। उन्होंने खुले आम विरोध करने की बात भी कही थी। लेकिन आंतरिक सूत्रों का कहना है कि वीपी सिंह और राकेश में अब संधि हो गयी है। बहुगुणाजी पर शक शुबहा करने का मुख्य कारण उनका इलाहाबाद के बाहर रहना है। बहरहाल चुनाव के समीप उनके चुनाव-प्रचार में शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी उनके विरोधी ऐसी अफवाह फैलाने से बाज नहीं आयेंगे कि वह नहीं चाहते कि वीपी सिंह का इलाहाबाद की सीट पर कब्जा हो और वह यह चुनाव जीतकर विपक्ष के अपरिहार्य नेता हो जायें। ऐसे आरोप अकेले बहुगुणा पर ही नहीं लग रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील का कहना था, "क्या आप सोचते हैं कि कोई विपक्षी दिग्गज मन से चाहेगा कि राजा विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बन जाये ?" बहरहाल देवी लाल, बीजू पटनायक, हेगड़े, जार्ज फर्नांडीस और मधु दंडवते आदि को वीपी सिंह को नेता मानने में कोई गुरेज नहीं। देवी लाल के प्रस्तावित 'राष्ट्रीय मोर्चा' और उसके नेता वीपी सिंह को बनाये जाने की पेशकश पर इन नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी। देवी लाल तो नामांकन के दिन भी इलाहाबाद उड़ कर आये थे।

हारजीत का फैसला : इलाहाबाद में सर्वाधिक मतदान (५७ प्रतिशत) १९८४ में हुआ था। लेकिन इस समय स्थितियां वैसी नहीं और फिर भयंकर गर्मी का मौसम है, इसलिए अनुमान है कि ४० प्रतिशत से अधिक मतदाता शायद ही वोट डालें। यदि यह मान भी लिया जाये कि सुनील शास्त्री को कायस्थ वोट थोक के भाव मिलेंगे, राजा को ठाकुरों के पूरे वोट मिलेंगे और कांशीराम को

अमिताभ बच्चन द्वारा किये गये आसमानी वादों के पूरा न होने से भी आम इलाहाबादी का कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। इसका लाभ राजा को मिलेगा।

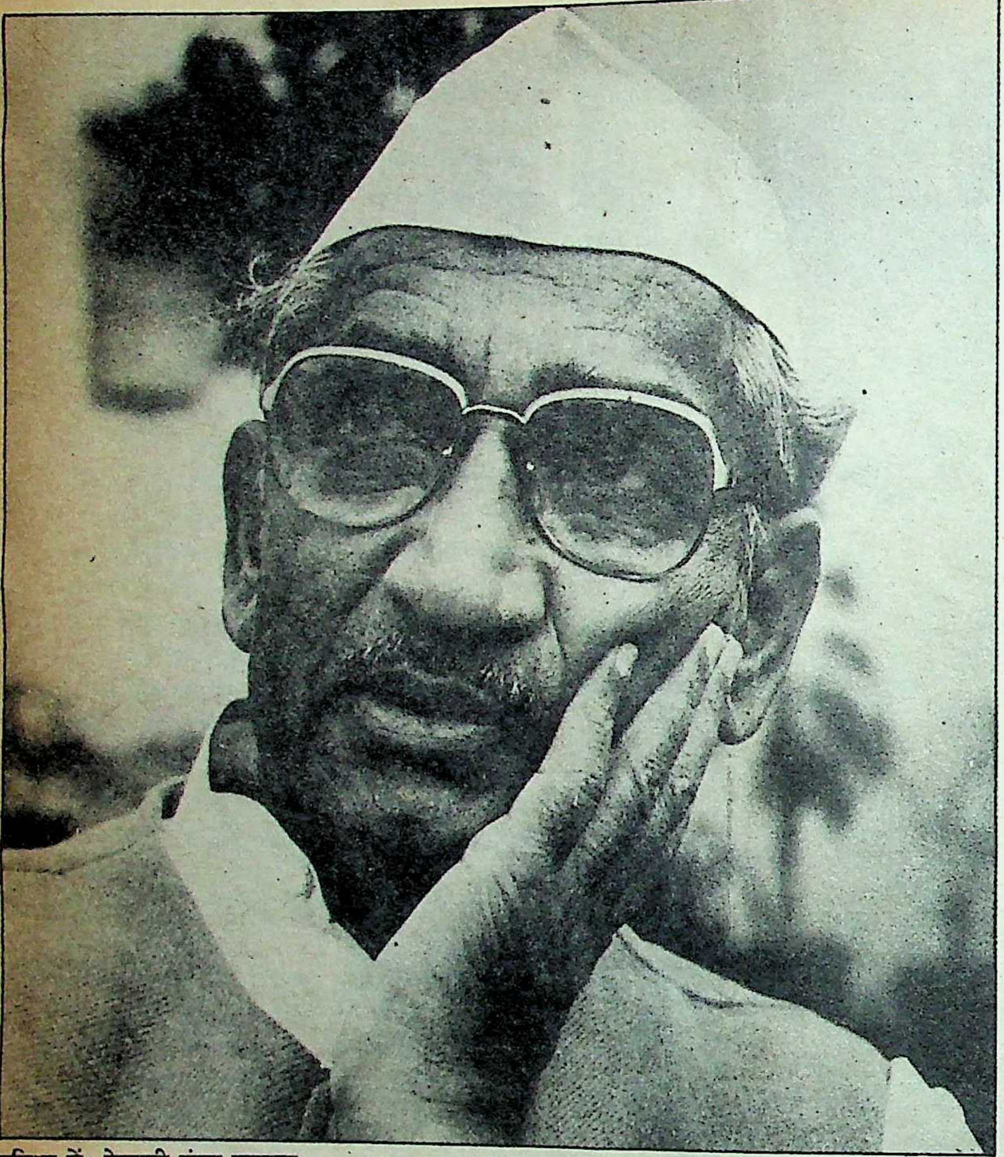

दुविधा में: हेमवती नंदन बहुगुणा

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

हरिजनों के एक समुदाय के वोट मिलेंगे, तो ब्राह्मणों, मुस्लिमों, यादवों और कुर्मियों के वोट निर्णायक होंगे। पिछड़ों के वोट लोकदल के पास रहे हैं। अजीत सिंह (जनता पार्टी) और लोकदल-ब के देवीलाल दोनों ही वीपी सिंह के साथ हैं। ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों नेताओं की अपील का असर पिछड़ों पर नहीं होगा। यद्यपि वीपी सिंह के मुख्यमंत्री-काल में डकैती अभियान से पिछड़ों का एक वर्ग क्षुब्ध जरूर है, लेकिन इस क्षोभ का अधिक असर नहीं लगता। मुस्लिम वर्ग कांग्रेस से बेहद नाराज है। रही-सही कसर ईद के दिन इलाहाबाद के मुस्लिम बहुल मोहल्लों में पानी के गायब होने से पूरी हो गयी। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में अरुण नेहरू की भूमिका और शाहबानो मामले में मोहम्मद आरिफ के रुख से भी मुस्लिम राजा से दूर हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही नेता जनमोर्चा में जरूर हैं, पर इलाहाबाद में सक्रिय नहीं हैं। राजा के साथ भाजपा के होने से भी मुस्लिम खेमे में राजा के प्रति बेरुखी हो सकती है लेकिन इस सबके बावजूद प्रतिबद्ध कांग्रेसी मुसलमानों के अतिरिक्त कांग्रेस को इस समुदाय के वोट नहीं मिलेंगे। अधिकांश ब्राह्मण वोट यद्यपि कांग्रेस को जाते हैं, लेकिन बकौल एक जातिवादी विश्वविद्यालय प्राध्यापक के, अमिताभ बच्चन के कथित कायस्थवाद से क्षुब्ध ब्राह्मण फिर से किसी कायस्थ प्रत्याशी को जिताने में रुचि नहीं लेंगे।

अमिताभ बच्चन द्वारा किये गये आसमानी वादों के पूरा न होने से भी आम इलाहाबादी का कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। इसका लाभ राजा को मिलेगा। राजा व्यवस्था के बदलाव के जो सपने दिखा रहे हैं, उनसे भी लोग मोहित हो रहे हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की साख घटी है। कोई और चमत्कार नहीं हुआ, तो कांशीराम केवल वोट तोड़ने और हार जीत का अंतर घटाने में भूमिका निभायेंगे। कांशीराम ज्यादातर कांग्रेस के वोट बैंक (हरिजन) में सेंध लगायेंगे, जिसका लाभ राजा को मिलेगा। ऐसी स्थिति में अब तक पलड़ा राजा का ही भारी है। लेकिन 'माया' ने राजा से जब सवाल किया कि आपको खतरा किससे है, तो उनका एक मात्र उत्तर था, 'वीर बहादुर की हाथ की सफाई से।' यह तो चुनाव का नतीजा ही बतायेगा। ■

इलाहाबाद

इतिहास चुनावों का

इलाहाबादवासियों में १९८४ के लोकसभा चुनावों में अमिताभ बच्चन ने जो सरगर्मी पैदा की थी, इस उपचुनाव में उनके न रहने पर भी अन्य कारणों से वैसी सरगर्मी बरकरार है। उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमिताभ की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, लेकिन इस बार उनका इरादा इसी चुनाव मैदान में अमिताभ बच्चन को धूल चटाने का था, लेकिन अब वह उन सुनील शास्त्री को परास्त करने की जोड़तोड़ में जुट गये हैं, जिनसे उनके वैसे ही आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, जैसेकि राजीव गांधी के अमिताभ बच्चन से हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे बढ़ाने में लाल बहादुर शास्त्री ने जो भूमिका निभायी थी, वैसी ही भूमिका वीपी सिंह ने बैंक के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत सुनील शास्त्री को राजनीति में आगे बढ़ाने में निभायी थी। १९८० में वीपी सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सुनील शास्त्री को पहले उपमंत्री, फिर राज्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस-इ हलकों में इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जब श्रीमती ललिता शास्त्री का नाम लिया जा रहा था, तो वीपी सिंह ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वह श्रीमती शास्त्री के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वक्त-वक्त की बात है, आज वीपी सिंह श्रीमती ललिता शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री से लड़ने के लिए मजबूर हैं, तो सुनील शास्त्री की भी मजबूरी यही है कि जिन वीर बहादुर सिंह को उन्होंने भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था, उन्हीं की छत्रछाया में उन्हें यह चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वीर बहादुर सिंह भी जोड़तोड़ की राजनीति में अपना सानी नहीं रखते। इसका थोड़ा बहुत जलवा तो नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन इलाहाबाद के जिलाधीश-कार्यालय के सामने इलाहाबादवासियों ने देख लिया है। अमिताभ बच्चन को उस दिन इलाहाबाद नहीं आना था, लेकिन हर आदमी उन्हीं का इंतजार कर रहा था और उस दिन वह सब कुछ हो गया जो इलाहाबाद के चुनावी इतिहास में कभी

नहीं हुआ था। कांग्रेस-इ प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र भरने के तत्काल बाद उन्हीं लोगों ने कांग्रेस-इ के मंच को ढहा दिया और पुलिस की लाठियां खायीं, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस-इ (अमिताभ) की विजय में निर्णायक भूमिका निभायी थी। इस उपचुनाव में एक ओर जहां वीरबहादुर सिंह का कूटकौशल अपना रंग दिखायेगा, तो दूसरी ओर इस कूटकौशल का जवाब देने में सक्षम इलाहाबाद के चंदन हेमवतीनंदन बहुगुणा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है जो चुनाव में खड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन यदि वीपी सिंह हारते हैं, तो इसका कलंक-टीका उनके माथे पर भी लगेगा। इस तरह चुनाव विशारद महारथियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार के सारे साधन जहां सुनील शास्त्री की ओर हैं, वहीं प्रायः संपूर्ण विपक्ष वीपी सिंह के साथ खड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार इलाहाबादवासी इस उपचुनाव में गहरी दिलचस्पी लेंगे, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है कि इस बार मतदान काफी कम होगा। इलाहाबाद के चुनावों में यद्यपि दिग्गज हस्तियां खड़ी होती रही हैं, लेकिन अभी तक हुए दस लोकसभा चुनावों में सिर्फ १९६७ (५३.१९ प्रतिशत) और १९८४ (५७ प्रतिशत) को छोड़कर कभी भी पचास प्रतिशत से अधिक मतदाता मत देने नहीं निकले।

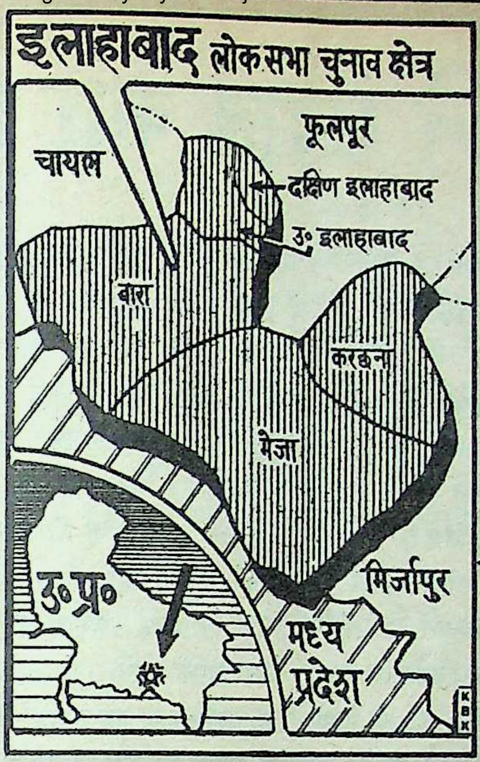

इस उपचुनाव में तो सारे राष्ट्रीय विपक्ष की साख दांव पर लग गयी है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह हार जाते हैं, तो बहुत संभव है कि राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर देंगे, लेकिन यदि सुनील शास्त्री हार जाते हैं, तो भी इसके असर से दिल्ली बच नहीं पायेगी।

दलीय स्थिति: इलाहाबाद में हुए दस लोकसभा चुनावों में १९७४ और १९७७ को छोड़कर (जनेश्वर मिश्र ने श्रीमती गांधी के वकील एचसी खरे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को हराया था) विजयश्री हमेशा कांग्रेस को मिली, लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस को लोहे के चने चबाने पड़े हैं। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही करीब दो लाख वोटों से जीते अन्यथा जवाहरलाल नेहरू (१९५२) ३१८७१ मतों से, लाल बहादुर शास्त्री (१९५७ और १९६२) क्रमशः ५६ हजार व ६८ हजार मतों से तथा हरिकृष्ण शास्त्री और केपी तिवारी बमुश्किल १४, ५४४ और ४६, ६९१ मतों से विजयी रहे थे। स्पष्ट है, इलाहाबाद में विपक्षी कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर देते रहे हैं। प्रभावक्षेत्र के लिहाज से यहां कांग्रेस के बाद समाजवादियों का नंबर आता है और भाजपा तीसरे स्थान पर है। समाजवादी छवि के प्रत्याशियों ने जहां कांग्रेस को दो बार हराया है और सात बार सीधी टक्कर दी, वहीं भाजपा ने (तब जनसंघ) सिर्फ एक बार १९६२ में लाल बहादुर शास्त्री को सीधी टक्कर दी थी और १९६७ और १९८० में इसने क्रमशः तीसरे स्थान पर रहकर २० हजार और ३३ हजार ८ मत प्राप्त किये थे। यदि उक्त दोनों अवसरों पर भाजपा विपक्ष के वोट न काटती, तो किसी भी सूरत में हरिकृष्ण शास्त्री (१९६७) जीत नहीं सकते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह १९७७ की तरह १९८० में भी हार जाते। इलाहाबाद से सुनील शास्त्री का परिवार तीन चुनाव लड़कर (१९५७, १९६२, १९६७) जीत चुका है। इस लिहाज से इस सीट को सुनील शास्त्री की पारिवारिक सीट कहा जा सकता है, इसके बावजूद उनकी जीत आसान नहीं है, क्योंकि न तो अब १९८४ जैसी सहानुभूति लहर (श्रीमती गांधी की हत्या से उत्पन्न) है और न ही सुनील शास्त्री के पास अमिताभ जैसा फिल्मी ग्लैमर है।

जातीय समीकरण: इलाहाबाद में हुए पिछले दस चुनावों में जाति के आधार पर वोटों को गिरोहबंद करने की कोशिश होती रही हैं, लेकिन यहां से विजयी या पराजित होनेवाले राष्ट्रीय दलों के किसी नेता ने जातिवाद को चुनावों में बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव दंगल में उतरे कांशीराम का सारा चुनाव-प्रचार जातिवादी जहर घोलने का कारण बनता जा रहा है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इलाहाबाद के मतदाताओं पर जाति के आधार पर वोट देने की अपीलों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या ८ लाख ४३ हजार ७७५ है। जाति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाये, तो इनमें सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों (१ लाख, ३८ हजार) और हरिजनों (१ लाख ९१ हजार) की है, जबकि यहां कायस्थ-६० हजार, ठाकुर-५६ हजार, मुस्लिम-८५ हजार और अहीर-८१ हजार हैं। यहां हुए दस चुनावों में चार बार कायस्थ, पांच बार ब्राह्मण तथा एक बार ठाकुर ने चुनाव जीता है। इस उपचुनाव में ठाकुर बनाम ब्राह्मणवाद को हवा देने की कोशिशें हो रही हैं।

इलाहाबाद वह शहर है जो उत्तर प्रदेश में होते हुए भी राष्ट्रीय महत्व का शहर रहा है। धार्मिक दृष्टि से 'संगम' के कारण करोड़ों हिंदुओं के लिए यह पवित्र स्थान है, तो राजनीतिक रूप से इसकी दिलचस्पी राष्ट्रीय मामलों में रही है। मुगलों के जमाने में यह दिल्ली-तख्त के बागियों का गढ़ रहा और ब्रिटिश जमाने में तो इस शहर में होनेवाली स्वातंत्र्य सेनानियों की गतिविधियों के धमाके न केवल दिल्ली में, बल्कि लंदन तक महसूस किये जाते थे। आजादी के बाद तो इस शहर की राष्ट्रीय भूमिका के कारण इसे आजाद भारत की राजधानी बनाने की मांग भी जोरों से उठी थी। बहरहाल, यह शहर राजधानी तो नहीं बन सका, लेकिन जिन्हें भी इस शहर के लोगों ने चुनावों में विजयी बनाया वे देश और प्रदेश की राजधानियों में सत्ता-शीर्ष पर पहुंचे। इस उपचुनाव में तो सारे राष्ट्रीय विपक्ष की साख दांव पर लग गयी है और वह तो यहां तक जा रहा है कि यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह हार जाते हैं, तो बहुत संभव है कि राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर देंगे, लेकिन यदि सुनील शास्त्री हार जाते हैं, तो भी इसके असर से दिल्ली बच नहीं पायेगी। ■

अमिताभ ने मैदान क्यों छोड़ा ?

उस दिन २३ मई को इलाहाबाद में जिलाधीश के कार्यालय के अंदर-बाहर ४५° सेल्सियस की उमस भरी भीषण गर्मी में हजारों लोगों की भीड़ बड़ी बेताबी से जिस एक व्यक्ति का इंतजार कर रही थी, वही अमिताभ बच्चन उस दिन नहीं आये। पूरे यकीन के साथ उनका इंतजार वीपी सिंह सहित उनके वे विरोधी भी कर रहे थे जो उन्हें इस चुनाव में मजा चखाना चाहते थे। कांग्रेस-इ के नेता तो उपस्थित भीड़ को 'आंखों देखा' जैसा हाल सुनाते हुए बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन कहां-कहां से होते हुए किस तरह वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन बच्चन नहीं आये और अंतिम क्षणों में सुनील शास्त्री ने कांग्रेस-इं की ओर से इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। क्या अमिताभ बच्चन ने हार जाने के भय से स्वयं मैदान छोड़ दिया? या उन्होंने राजीव गांधी की इच्छा से ऐसा किया? क्या यह फैसला उन्होंने अंतिम क्षणों में लिया या राजीव गांधी काफी पहले उन्हें उपचुनाव में न उतारने का मन बना चुके थे? यदि ऐसा था, तो जिलाधीश कार्यालय के बाहर खड़ी बेकरार भीड़ से कांग्रेस-इ नेता झूठ क्यों बोलते रहे? राजीव गांधी ने बच्चन को इस उपचुनाव में न उतारकर उन्हें चुनाव सभाओं में होनेवाली फजीहत और संभावित हार की जलालत से बचाया है या उन्हें पार्टी के हित को देखते हुए अलविदा कह दिया है? अमिताभ के चुनाव मैदान में न उतरने से क्या कांग्रेस-इ की चुनाव संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा?

पार्टी के प्रचार तक के लिए नहीं आये: १९८४ में अमिताभ

२३ मई को इलाहाबाद के जिलाधीश कार्यालय के बाहर नामांकन पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन जो दृश्य उपस्थित हुआ था, वह अद्भुत था। कांग्रेस-इ के जिन नेताओं ने अमिताभ बच्चन को अनुपयुक्त और हार की प्रबल संभावनाओं से युक्त प्रत्याशी घोषित किया था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे 'अमिताभ लाओ' का नारा लगा रही भीड़ को सचाई बता पाते। कांग्रेस-इ मंच पर खड़े कुछ नेता (जैसाकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया है) जानते थे कि अमिताभ बच्चन चुनाव में खड़े नहीं हो रहे और उस दिन उनका इलाहाबाद आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, फिर भी वे मंच से लोगों को बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन बस पहुंचने ही वाले हैं। राजनीति का अमिताभ पर कोई असर हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इलाहाबाद की राजनीति पर उनका ऐसा फिल्मी असर हुआ कि उस दिन वहां उपस्थित पक्ष-विपक्ष के सारे नेता, कार्यकर्ता और दर्शक एक ऐसी फिल्म के पात्र बन गये थे, जिसकी बस शूटिंग ही होनी बाकी थी। भीषण गर्मी में पांच घंटों तक वे सब ऐसी कहानी में हिस्सेदार थे, जिसका असलियत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था।

जिला प्रशासन भी इस बेवजूद कथानक का एक पात्र बन गया था। उसके सूत्र भी स्वीकार करते हैं कि उनसे कहा गया था कि अमिताभ बच्चन २२ मई की रात्रि में कभी भीं इलाहाबाद पहुंच सकते हैं। २३ मई को प्रातः विद्याचरण शुक्ल और रामधन इलाहाबाद पहुंच रहे थे और उनके ठहरने की व्यवस्था भी सर्किट हाउस में थी। इसलिए अमिताभ के ठहरने की व्यवस्था 'हेडल रेस्ट हाइस' में की गयी थी। उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम था, क्योंकि जिला प्रशासन को आशंका थी कि वीपी सिंह समर्थक अमिताभ का घेराव कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दे रखी थी कि वह अमिताभ को कार से चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे।

नामांकन पत्र दाखिल करने में जब सिर्फ तीस मिनट रह गये, तब कहीं पूरे माहौल का स्वप्न भंग हुआ और असलियत सामने आयी कि अमिताभ बच्चन नहीं, बल्कि सुनील शास्त्री इलाहाबाद के संसदीय उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह का मुकाबला करेंगे। इस रहस्योद्घाटन के बाद जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो कुछ हुआ, वह भी कांग्रेस-इ के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। जैसे ही सुनील शास्त्री ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, वैसे ही बच्चनप्रेमी कांग्रेस-इ कार्यकर्ताओं और अमिताभ फैंस एसोसियेशन के सदस्यों ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि कांग्रेस-इ का मंच टूट गया तथा कनातें और बल्लियां भरभरा कर गिर पड़ीं। और-तो-और भूतपूर्व सांसद केपी तिवारी ने तो कांग्रेस-इ मंच से ही अपने असंतोष का चिल्लाकर इजहार किया था। बच्चन-विरोधियों ने भी इस उपद्रव में खुलकर साथ दिया और माहौल बद से बदतर हो गया। दो दिनों तक सुनील शास्त्री के खिलाफ बच्चन प्रेमियों का हुड़दंग जारी रहा।

संदेह का माहौल : यह सारा ड्रामा क्या महज इसीलिए किया गया था जिससे वीपी सिंह को अंतिम क्षणों तक अमिताभ बच्चन के आने का भ्रम बना रहे और वह चुनाव मैदान से हटने न पायें, लेकिन उस दिन जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो कुछ हुआ, उससे क्या सुनील शास्त्री की विजय की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? संभवतः इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए राजीव गांधी ने अपने विश्वस्त मित्र रोमी चोपड़ा, कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद और उपचुनाव के पर्यवेक्षक सीताराम केसरी को इलाहाबाद रवाना किया था। बताया जाता है कि रोमी चोपड़ा की सलाह पर ही राजीव गांधी या उनके किसी सहयोगी ने अमिताभ बच्चन से संभवतः कहा कि वह इलाहाबाद में अपने फैंस को फोन करके शांत होने के लिए कहें। तदनुसार ही संभवतः २६ मई को फैंस एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पारित कर सुनील शास्त्री के समर्थन में कार्य करने की घोषणा कर दी।

फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि बधावन ने स्वीकार किया कि अमिताभ ने उन्हें सुनील शास्त्री को सहयोग देने का निर्देश दिया है। दो दिन पहले तक अमिताभ के फैंस जो उपद्रव कर रहे थे, क्या इसके लिए खुद अमिताभ बच्चन ने उन्हें उकसाया था? २४ मई को गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अमिताभ यूरोप में इलाज करा रहे हैं, लेकिन अगले दिन पीटीआई ने खबर दी कि अमिताभ बंबई में 'तूफान' फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। गुलाम नबी आजाद ने झूठ क्यों बोला? इन सवालों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न खेमों में दहशत फैला दी

और कांग्रेस-इ आलाकमान के इरादों के प्रति संदेह का माहौल पैदा हो गया।

अमिताभ के विरोधी : अमिताभ को नापसंद करनेवालों में इलाहाबाद के भूतपूर्व विधायक अशोक वाजपेयी के साथ-साथ मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह भी शामिल हैं। वाजपेयी इस बात को भूले नहीं हैं कि अमिताभ ने कभी दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्हें इलाहाबाद की राजनीति से उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी और वीरबहादुर सिंह से अमिताभ की अनबन जगजाहिर है। प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अमिताभ बच्चन जब सांसद थे, तो वह सुपर चीफ-मिनिस्टर की तरह आचरण करते थे जो वीरबहादुर सिंह के लिए अपमानजनक था। ये नेता बताते हैं कि एक बार जब वीरबहादुर सिंह अमिताभ से बंगलौर मिलने गये थे, उन्हें किस तरह छह घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और जब अमिताभ मिले भी, तो मुख्यमंत्री से बड़े सामान्य ढंग से पेश आये। यह भी माना जा रहा है कि वीरबहादुर सिंह को सुनील शास्त्री का कांग्रेस-इ प्रत्याशी बनाया जाना पसंद नहीं, क्योंकि यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि वह सुनील शास्त्री को अक्षम मंत्री कहते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर चुके हैं और सुनील शास्त्री उन्हें भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहकर मंत्री पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। इसी प्रकार कांग्रेस में बच्चन-विरोधियों की सूची काफी लंबी है। इन सभी को यह आशंका है कि उनके साथ कूटनीतिक चाल खेली जा रही है और बच्चन का राजनीतिक संन्यास एक अस्थायी दौर है तथा जैसे ही सुनील शास्त्री उपचुनाव में विजयी होंगे, अमिताभ बच्चन को फिर से राजनीति में सक्रिय कर दिया जायेगा। तब वीरबहादुर सिंह जैसे उन सब लोगों पर आफत टूट पड़ेगी जो बच्चन के विरोधी रहे हैं। नरसिम्हाराव और नारायण दत्त तिवारी जैसे बच्चन विरोधी केंद्रीय नेता भी आशंकित हैं। सांसद जीतेंद्र प्रसाद, पीएन सुकल और पुष्पराज सिंह ने तो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने के बाद सुनील शास्त्री के पक्ष में अपनी राय दी थी। ये सभी नेता यह जानने को उत्सुक हैं कि अमिताभ को चुनाव मैदान से क्यों हटाया गया, राजनीतिक रूप से अब अमिताभ और राजीव गांधी के संबंध कैसे हैं, और क्या दोनों के रास्ते स्थायी रूप से अलग-अलग हो गये हैं?

> **एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि अमिताभ बच्चन यदि उपचुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके जीतने की उम्मीद ३० प्रतिशत है और साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह चुनाव एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का अखाड़ा बन जायेगा और देशी-विदेशी संवाददाताओं की पूरी निगहबानी में राजीव गांधी भी इसका निशाना बनेंगे। इसी आशंका ने संभवतः निर्णायक भूमिका निभायी।**

राजीव-अमिताभ वार्ता : प्रत्याशी के नामों पर अंतिम फैसला लेने के लिए २१ मई को दिल्ली में कांग्रेस-इ संसदीय दल की बैठक हुई थी। इलाहाबाद संसदीय सीट का टिकट पाने की उम्मीद लिये इलाहाबाद के भी कुछ नेता दिल्ली में जमे थे। इन लोगों का दावा है कि अमिताभ बच्चन ने २० मई को रात्रि भोज पर राजीव गांधी से लंबी बातचीत की थी और यह बातचीत आधी रात के बाद तक चलती रही थी। इनका कहना है कि उनकी सूचना

इंका के उखड़े तंबू: नामांकन के दिन मचे उत्पात का परिणाम

छाया: राजेंद्र कुमार

सही है। वे टाइम्स आफ इंडिया की इस खबर को असत्य बतलाते हैं, जिसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन विदेश में हैं और २२ मई को उनके दिल्ली लौटने की संभावना है। इन लोगों के अनुसार यह झूठी खबर इस समाचार पत्र में इस इरादे से प्रकाशित करायी गयी थी, जिससे वीपी सिंह जहां गफलत में रहें, वहीं वह इस मुगालते में उत्साहपूर्वक इस बात को भी दोहराते रहें कि अमिताभ निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे अमिताभ के चुनाव न लड़ने की स्थिति में वीपी सिंह की विश्वसनीयता को भारी चोट पहुंच सके।

कांग्रेस-इ के अन्य सूत्र अमिताभ-राजीव वार्ता की बात का खंडन करते हुए स्वीकार करते हैं कि २० और २१ मई की रात में विदेश (संभवतः लंदन) से अमिताभ ने राजीव से टेलिफोन पर बातचीत की थी और इसी बातचीत में राजीव गांधी ने उन्हें बताया था कि सुनील शास्त्री को इलाहाबाद संसदीय सीट के लिए कांग्रेस-इ का प्रत्याशी चुना गया है। ये सूत्र यह भी कहते हैं कि अमिताभ एक सप्ताह तक विदेश में रहने के बाद २४ मई को बंबई पहुंच गये थे। यह तथ्य भी गुलाम नबी आजाद को झूठा साबित कर देता है जो २४ मई को कह रहे थे कि अमिताभ बीमार हैं और युरोप में अपना इलाज करा रहे हैं। आजाद और सीताराम केसरी युरोप का नाम तो ले रहे थे, लेकिन वे यह नहीं बतला पा रहे थे कि अमिताभ युरोप के किस देश में अपना इलाज करा रहे हैं।

बंबई के स्वतंत्र सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार बच्चन १७ मई को मुख्यतः अपनी सेहत की जांच कराने के लिए विदेश रवाना हो चुके थे और २०-२१ मई की रात में वह दिल्ली लौटे थे। २२ मई को वह बंबई चले गये और २४ मई से उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म 'तूफान' की शूटिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यह सूचना कहीं अधिक विश्वसनीय लगती है और इलाहाबाद के स्थानीय नेताओं की इस सूचना से भी मेल खाती है कि अमिताभ राजीव से २०-२१ मई की रात में मिले थे।

लेकिन अमिताभ फैंस एसोसियेशन के सूत्र ने जो जानकारी दी, वह सारे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। एसोसियेशन के एक सदस्य के अनुसार जब उसने यह जानने के लिए कि अमिताभ चुनाव में खड़े हो रहे हैं या नहीं, उन्हें दिल्ली से बंबई फोन किया, तो अमिताभ ने यह कह कर टेलिफोन का रिसीवर रख दिया था कि २४ मई को विदेश से लौटने के बाद वह इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह बातचीत अमिताभ के विदेश रवाना होने के कई दिन पूर्व की है। इसका मतलब है कि वह नामांकन पत्र भरे जाने के कम-से-कम दस दिन पहले से जानते थे कि वह उपचुनाव के मैदान से बाहर हैं, फिर फैंस एसोसियेशन के कार्यकर्ता उनकी उम्मीदवारी का पता लगाने के लिए नामांकन पत्र भरे जाने के अंतिम दिन (२३ मई) और अंतिम क्षणों तक अमिताभ के दिल्ली और बंबई के ठिकानों पर फोन क्यों खटखटाते रहे। १५ मई को 'अमिताभ लाओ' का नारा लगाते हुए फैंस एसोसियेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज एक्सप्रेस को ढाई घंटों तक रोककर क्यों रखा? ऐसा हुड़दंग मचाने के लिए उन्हें कौन उकसा रहा था और यदि अमिताभ के फैंस स्वयंस्फूर्त प्रेरणा से यह सब कर रहे थे, तो फिल्म स्टार नें उन्हें तब क्यों नहीं रोका, जैसाकि उन्होंने अब फैंस एसोसियेशन के कार्यकर्ताओं को सुनील शास्त्री के साथ सहयोग करने की हिदायत दी है।

राजनीति को तिलांजलि: १९८४ में संगम-पूजन करते हुए बच्चन दंपती

छाया : एसके यादव

प्रत्याशी का चयन : सचाई शायद ही कभी सामने आये, लेकिन अंदाजा यह है कि अमिताभ की उम्मीदवारी के सवाल पर जोड़-तोड़ और बहस-मुबाहसों का दौर मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अपनी चरम सीमा पर पहुच चुका था और शायद इसी वजह से कांग्रेस-इ के अधिकृत प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने में देरी की गयी। संभवतः यह देरी इसलिए भी की गयी, क्योंकि आलाकमान ने तय कर लिया था कि जितनी देर तक संभव हो सके इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव के कांग्रेस-इ प्रत्याशी का नाम गुप्त रखा जाये। इससे कई हलकों में व्याप्त इस संदेह की पुष्टि होती है कि अमिताभ अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी पार्टी में व्याप्त दबाव और इलाहाबाद के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अमिताभ के लिए अपनी गर्दन फंसाने का खतरा मोल लेने के इच्छुक नहीं थे। राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों का मोह त्यागना पड़ता है। राजीव गांधी इस नाजुक स्थिति में अपने को बचाना चाहते थे और यह भी नहीं चाहते थे कि अपने मित्र से उनके संबंध खराब हों। इसके लिए उन्होंने दूसरा तरीका अख्तियार किया।

चार गुप्तचर एजेंसियों को इलाहाबाद

संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने का जिम्मा सौंपा गया। डीआईजी स्तर के अधिकारियों को इलाहाबाद के संबंध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इन सूत्रों का दावा है कि स्थानीय गुप्तचर एजेंसी को छोड़कर शेष सभी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि अमिताभ बच्चन यदि उपचुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके जीतने की उम्मीद ३० प्रतिशत है और साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह चुनाव एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का अखाड़ा बन जायेगा और देशी-विदेशी संवाददाताओं की पूरी निगहबानी में राजीव गांधी भी इसका निशाना बनेंगे। इसी आशंका ने संभवतः निर्णायक भूमिका निभायी। राजीव गांधी अन्य राजनेताओं के समान यह भी जानते थे कि कांग्रेस-इ पार्टी नहीं चाहती कि पूरी पार्टी को सिर्फ एक व्यक्ति के लिए दाव पर लगा दिया जाये। पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर बड़ी सुगबुगाहट थी। अतः राजीव गांधी ने यही बेहतर समझा कि सांसदों को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का राजनीतिक जायजा लेने के लिए कहा जाये। इन सभी ने अमिताभ बच्चन की उम्मीदवारी के विरोध में अपनी राय दी। पीएन सुकुल, जीतेंद्र प्रसाद, तरुणकांति घोष, श्रीपत मिश्र भी इलाहाबाद का जायजा लेनेवाले सांसदों में शामिल थे। अधिकांश सांसदों ने सुनील शास्त्री के पक्ष में राय दी थी। इसका अर्थ यह है कि चुनाव-तिथि की घोषणा होने के काफी पहले से ही राजीव गांधी को वैकल्पिक प्रत्याशी का सुझाव मिल चुका था। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की कि चुनाव मई से जून तक के लिए सरक जायें। उस समय यह अफवाह फैलायी गयी थी कि कांग्रेस-इ की प्रदेश इकाई बच्चन के पक्ष में माहौल बनाने और उनके विरुद्ध पनपे असंतोष को शांत करने के लिए समय चाहती है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने अपने समूचे मंत्रिमंडल और सौ कांग्रेसी विधायकों के साथ पदयात्राएं कीं, जहां उनका स्वागत पत्थरों और विरोध प्रदर्शनों से हुआ। क्या इन पदयात्राओं का मकसद यह साबित करना था कि माहौल अमिताभ बच्चन के खिलाफ है? जिससे अमिताभ को टिकट मिलने की बची-खुची संभावनाएं भी समाप्त हो जायें। २४ मई को उत्तेजना के क्षणों में अमिताभ बच्चन फैंस एसोसियेशन के एक सदस्य ने वीरबहादुर सिंह पर अमिताभ के विरुद्ध माहौल बनाने का आरोप लगाया, लेकिन राजीव गांधी के पास तो अमिताभ को दिखाने के लिए पर्याप्त लिखित रिपोर्टें थीं और वैसे भी इस क्षेत्र का तो अनेक बार जायजा लिया जा चुका था और कहा जा सकता है कि या तो राजीव गांधी अमिताभ को चुनाव मैदान से हट जाने के लिए कहने में दिक्कत महसूस कर रहे थे या बच्चन या उनके परिवार के सदस्य जोर दे रहे थे कि अमिताभ को अपनी बिगड़ी छवि को सुधारने का एक अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। दोनों ही बातें राजीव गांधी को माफिक नहीं लग रही थीं। अतः पिछले चार सालों में पहली बार प्रत्याशी चयन के लिए पारंपरिक प्रक्रिया अपनायी गयी। सर्वप्रथम संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करने के लिए प्रदेश और जिला कांग्रेस समिति की बैठक आयोजित की गयी और अंतिम निर्णय लेनें का उत्तरदायित्व राजीव पर छोड़ दिया गया। दिल्ली में भी इस संबंध में अनेक बैठकें हुईं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद, सीताराम केसरी, गुलाम नबी आजाद आदि इन बैठकों में सक्रिय रहे। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि २०-२१ मई की रात में ७ रेसकोर्स रोड में अमिताभ और राजीव गांधी के बीच टेलिफोन या रात्रि भोज पर क्या बातें हुईं? बच्चन विरोधी कांग्रेसी आश्वस्त होना चाहते हैं कि उस दिन अमिताभ से चुनाव न लड़ने के संबंध में ही बातें हुई थीं?

एक संभावना यह भी नजर आती है कि अमिताभ मतदाताओं का सामना करके बेइज्जत नहीं होना चाहते थे, इसलिए वह स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। इसका एक कारण मई-जून की भीषण गर्मी भी थी जो अमिताभ की सेहत के लिए घातक होती। यदि कारण ये ही हैं, तो अमिताभ विरोधियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ऐसा है?

अनेक बच्चनविरोधियों ने संकेत किया है कि पिछले अनेक महीनों से यह अफवाह जोरों पर थी कि अमिताभ की पत्नी जया, स्विट्जरलैंड में रह रहे उनके भाई अजिताभ और मां तेजी बच्चन इस बात की इच्छुक थीं कि अमिताभ इलाहाबाद का उपचुनाव जीतकर खानदान की इज्जत को बरकरार रखें। हाल ही जया बच्चन ने तो यहां तक कहा था कि अमिताभ को चुनाव लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए और फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। बताया जाता है कि केवल अमिताभ के पिता हरिवंशराय बच्चन ही इस राय के थे कि अमिताभ को किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि उनके विचार से राजीव गांधी और अमिताभ की राजनीतिक दोस्ती के कारण पहले ही बच्चन परिवार को काफी नुकसान पहुंच चुका है।

बच्चन भी भोले नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि राजीव गांधी के लिए अमिताभ का राजनीति में होना जितना जरूरी है, अमिताभ के लिए उससे कहीं अधिक जरूरी हैं कि राजीव गांधी सत्ता में रहें। ऐसी स्थिति में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि दोनों की दोस्ती टूट जायेगी या दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जायेंगे।

अमिताभ की शर्तें: विपक्ष द्वारा यह भी धारणा फैलायी गयी कि अमिताभ राजीव गांधी पर जोर डालते रहे कि वह तभी चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे, जब उनके भाई अजिताभ को फेरा (विदेशी मुद्रा अधिनियम) द्वारा लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया जायेगा और तभी राजीव गांधी भी आरोपों से मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि अमिताभ की विजय का मतलब इस बात पर जनादेश होगा कि अमिताभ और राजीव पाक-साफ हैं तथा बोफोर्स या पनडुब्बी घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। बताया जाता है कि लक्षद्वीप में इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर जनवरी में व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की शक्तिशाली सचिव सरला ग्रेवाल को यह देखने का कार्य सौंपा गया था कि अजिताभ यथाशीघ्र फेरा के आरोपों से मुक्त हो जायें।

इस धारणा के समर्थन में विपक्षी सूत्रों का कहना है कि अमिताभ बच्चन की 'शहंशाह' फिल्म मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए ही प्रदर्शित की गयी थी। फैंस एसोसिएशन के दो कार्यकर्ता अमिताभ को इलाहाबाद से फिर से टिकट देने की मांग को लेकर बोट्स क्लब (दिल्ली) पर अनशन कर चुके थे। इस दौरान बच्चन मौन धारणा किये रहे—जिसका अर्थ उनके विरोधियों ने यह लगाया कि बच्चन चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और वह चुनाव न लड़ें और दोस्ती भी न टूटे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजीव गांधी को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चयन की एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ी।

समझा जाता है कि २०-२१ मई की रात्रि में हुई अमिताभ-राजीव वार्ता में दोनों एक दूसरे की सहमति से एक नतीजे पर पहुंच चुके थे और दोनों सुनील शास्त्री को इलाहाबाद से चुनाव लड़वाने पर सहमत हो गये थे। २२ मई को राजीव गांधी बड़े सबेरे बिहार के दौरे पर निकल गये और रात में देर से लौटे थे। इसका मतलब है कि उन्होंने अमिताभ से सारी बातें साफ कर ली थीं और बातचीत के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया था।

दरअसल, बताया जाता है कि अमिताभ से बातचीत होने के बाद २१ मई को प्रातः ६ बजे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने निवास स्थान पर उत्तर प्रदेश के कई नेताओं—मोहसिना किदवई, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, हरिकृष्ण शास्त्री और अशोक वाजपेयी से इलाहाबाद के संभावित प्रत्याशी के संबंध में अलग-अलग बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने इस बातचीत में एक भी बार अमिताभ का नाम नहीं लिया। इसके बाद हुई संसदीय दल की बैठक में सिर्फ बूटा सिंह ने अमिताभ बच्चन के नाम का समर्थन किया, जबकि नरसिम्हाराव और वीरबहादुर सिंह ने विरोध। वीरबहादुर सिंह श्याम सूरत उपाध्याय को टिकट दिलवाने को उत्सुक थे, लेकिन राजीव गांधी ने संभावित प्रत्याशी के रूप में सुनील शास्त्री का भी नाम जोड़ दिया और इन दोनों में से किसे प्रत्याशी बनाया जाये, यह फैसला लेने का दायित्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर

लोकप्रियता का इम्तहान

छाया: आरसी कपूर

छोड़ दिया गया। दिल्ली में टिकट पाने की आशा में जमे अशोक वाजपेयी सरीखे बच्चन विरोधी नेता संतुष्ट थे कि अमिताभ चुनाव मैदान से बाहर हैं और श्यामसूरत उपाध्याय को टिकट मिलना निश्चित है। वह अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर इलाहाबाद लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव वी जार्ज ने एक धमाका कर दिया। इलाहाबाद कांग्रेस-इ के एक नेता ने दावा किया है कि जार्ज ने उनसे रात्रि सवा आठ बजे कहा था, "दिल्ली में जमे रहने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग इलाहाबाद जाकर अमिताभ के चुनाव प्रचार की तैयारी करें। प्रधानमंत्री ने अमिताभ के नाम को स्वीकृति दे दी है।" उक्त नेता ने उत्तर प्रदेश भवन में जाकर जब अन्य नेताओं को इसकी खबर दी, तो वहां मौजूद बच्चन विरोधियों में एक बार फिर हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि अशोक वाजपेयी इलाहाबाद लौटना स्थगित कर दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश के नेताओं को फोन खटखटाने लगे। उन्होंने राजीव गांधी से भी मिलने का समय मांगा। राजीव गांधी उनसे देर रात में मिले और आश्वस्त किया कि प्रत्याशी चयन का दायित्व संसदीय बोर्ड ने मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। वाजपेयी आश्वस्त होकर लौट आये और वीरबहादुर सिंह इतने चतुर तो हैं ही कि वह प्रधानमंत्री का यह संकेत समझ जायें कि उनकी पसंद सुनील शास्त्री हैं और वह ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर वीपी सिंह आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते और यही वजह थी कि वीरबहादुर सिंह ने सुनील शास्त्री का समर्थन कर दिया। लेकिन यह तथ्य अभी तक रहस्य बना हुआ है कि जार्ज ने अमिताभ की उम्मीदवारी की चर्चा उस रात उक्त नेता से क्यों की थी ? क्या इसका मतलब भी कांग्रेस-इ प्रत्याशी के संबंध में रहस्य को बरकरार रखना था। इसका एक तार्किक स्पष्टीकरण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस-इ आलाकमान अमिताभ बच्चन को सुनील शास्त्री के पक्ष में चुनाव प्रचार से दूर रखना चाहता था, क्योंकि उसे आशंका थी कि इससे चुनाव प्रचार में सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में फूट पड़ सकती है।

राजीव की रणनीति: सुनील शास्त्री को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे राजीव गांधी के दो मकसद थे। राजनीतिक रूप से वह चाहते थे कि सुनील शास्त्री उपचुनाव में विजयी हों और व्यक्तिगत तौर पर उनकी इच्छा थी कि उनके दोस्त अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद में अपमानित न होना पड़े। लेकिन निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में अमिताभ को न उतारकर राजीव गांधी युद्ध का पहला दौर हार चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।

वीपी सिंह का लक्ष्य केवल बच्चन नहीं हैं, बल्कि उनकी नजर राजीव गांधी पर है। राजीव गांधी इस बात को भलीभांति जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कूटनीतिक रूप से पीछे हटने, तैयारी करने और ताजादम होकर १६ जून को अंतिम युद्ध लड़ने के लिए सुनील शास्त्री को मैदान में उतारा है। जिस हथियार को वीपी सिंह अमिताभ बच्चन के खिलाफ घातक रूप से इस्तेमाल कर सकते थे, वह सुनील शास्त्री के विरुद्ध बेअसर हो गया है और वीपी सिंह को अपनी चुनावी रणनीति नये सिरे से बनानी पड़ी है। निश्चित रूप से राजीव गांधी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और बच्चन भी भोले नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि राजीव गांधी के लिए अमिताभ का राजनीति में होना जितना जरूरी है, अमिताभ के लिए उससे कहीं अधिक जरूरी है कि राजीव गांधी सत्ता में रहें। ऐसी स्थिति में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि दोनों की दोस्ती टूट जायेगी या दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जायेंगे। कम-से-कम फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। अमिताभ की उम्मीदवारी के सवाल पर जो भी नाटक खेला गया, उसमें दोनों की परस्पर सहमति थी और दोनों के व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिए वक्त की जरूरत समझकर ही इस नाटक का तानाबाना बुना गया था।

बहरहाल, अमिताभ-राजीव गांधी के संबंधों में इलाहाबाद उपचुनाव से एक मोड़ जरूर आ गया है। १६ जून को होनेवाले मतदान के परिणाम जो कुछ भी हों, इसका असर काफी लंबे समय तक बरकारार रहेगा और बच्चन के समर्थकों और विरोधियों की नजरें इन दोनों की दोस्ती का जायजा लेती रहेंगी। यह तो वक्त ही बतलायेगा कि अमिताभ ने राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया है या थोड़ा ठहरकर वह पूरे जोशोखरोश से एक बार फिर इलाहाबाद की राजनीति में अवतरित होंगे।

सुनील शास्त्री मैदान में क्यों ?

राजीव की पसंद : सुनील शास्त्री

कांग्रेस-इ ने औपचारिक मुनादी भले ही यह की हो कि इलाहाबाद के लिए उम्मीदवार का चयन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और पार्टी अध्यक्ष महावीर प्रसाद करेंगे, लेकिन यह सच है कि सुनील शास्त्री को स्वयं राजीव गांधी ने पसंद किया था। मुख्यमंत्री तो चाहते थे कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय खड़े हों। यह भी सच है कि स्वयं उपाध्याय भी चाहते थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाये, ताकि हारने के बावजूद इलाहाबाद की सीट पर भविष्य में उनके दावे का आधार बन सके। फिर कांग्रेस प्रत्याशी पर होने वाली पैसों की बौछार का भी एक आकर्षण तो होता ही है।

हां, सुनील शास्त्री कतई नहीं चाहते थे कि उनको वीपी सिंह के खिलाफ प्रत्याशी बनाया जाये। वीपी सिंह और शास्त्री परिवार का घनिष्ठ संबंध है और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री वीपी सिंह को अपना पांचवां बेटा मानते थे। सिंह को राजनीति में शास्त्रीजी ही लाये थे। शास्त्रीजी से सिंह की पहली भेंट भारत-पाक युद्ध के बाद १९६५ में हुई थी। उक्त वर्ष २७ दिसंबर को वीपी सिंह ने अपने पैतृक महल में शास्त्रीजी के सम्मान में एक आयोजन किया था और अपना अंगूठा चीर कर शास्त्रीजी को रक्त तिलक किया था। शास्त्रीजी के प्रिय संस्थान सेवा निकेतन की पहली शाखा भी सिंह के मांडा स्थित महल में ही खुली थी। सिंह की राजनीति पर भी शास्त्री के आदर्शों की छाप है। मुख्यमंत्री-पद से सिंह के इस्तीफे की तुलना रेल दुर्घटना के बाद शास्त्रीजी के रेलमंत्री-पद से इस्तीफे से की जा सकती है। शास्त्रीजी ने 'जय जवान, जय किसान' का अमर नारा दिया था। जवानों के प्रति शास्त्रीजी के आदरभाव का प्रभाव सिंह पर भी है। बोफोर्स दलाली प्रकरण को उन्होंने इसीलिए मुद्दा बनाया। इसे वह जवानों के साथ धोखा मानते हैं।

राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की छत्रछाया में वीपी सिंह पले हैं, वैसे ही सिंह के संरक्षण में सुनील शास्त्री का राजनीतिक पालन-पोषण हुआ है। सुनील शास्त्री पहली दफा वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे और वह उनके काफी करीब थे।

इसी कारण सुनील शास्त्री नहीं चाहते थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाये। लेकिन राजीव गांधी का अपना गणित था। अमिताभ बच्चन के नाम पर दिल्ली और लखनऊ से ज्यादा स्थानीय कांग्रेसी बगावत पर उतारू थे। राजीव गांधी यह भी चाहते थे कि चुनाव को कम-से-कम प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया जाये। दूसरी ओर वीपी सिंह की विश्वसनीयता पर चोट करना भी उनका मकसद था। वीपी सिंह बार-बार कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन के खड़े होने पर ही वह चुनाव लड़ेंगे। फलस्वरूप राजीव गांधी ने सुनील शास्त्री को मैदान में उतारा।

सुनील शास्त्री को खड़ा करने के पीछे मुख्य रूप से दो मकसद रहे हैं। पहला, वीपी सिंह के हमले को कमजोर करना, दूसरा, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की छवि को भुनाना। शास्त्री-परिवार से वीपी सिंह का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वह शास्त्री पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते। लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से दो बार जीते थे—१९५७ और १९६२ में। फिर लाल बहादुर शास्त्री के प्रति सारे देश में अगाध श्रद्धा है—इलाहाबाद में तो और भी ज्यादा है। इसलिए उनके नाम पर उनके बेटे के लिए वोट मांगे जा सकते थे। यह बात दूसरी है कि पिछले २२ सालों में शास्त्रीजी को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। इलाहाबाद के महत्वपूर्ण आयोजनों में कभी उनका चित्र भी नहीं टांगा, लेकिन इस समय पोस्टरों में शास्त्रीजी के चित्र लगे हैं और उनके नाम के गाने बजाये जा रहे हैं। शास्त्रीजी के अतिरिक्त एक बार

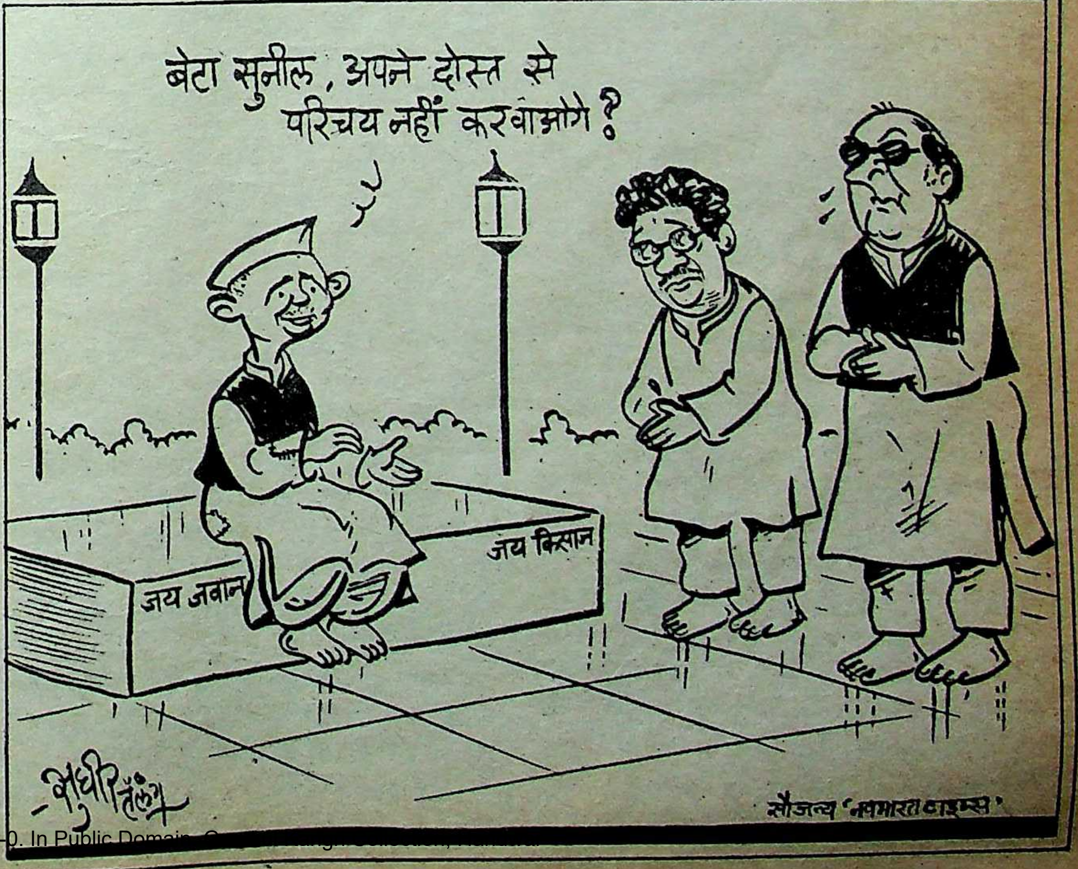
बेटा सुनील, अपने दोस्त से परिचय नहीं करवाओगे ?
जय जवान
जय किसान
सुधीर तैलंग

सौजन्य 'नवभारत टाइम्स'

दोस्ती का राज !

काफी अरसे से लोग राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की निराली और राजीव को नुकसान पहुंचाने वाली, दोस्ती की चर्चा करते रहे हैं। इलाहाबाद में संसदीय उपचुनाव के सिलसिले में इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि एक दिन जाने-माने पत्रकार ने मुझसे बड़े ताज्जुब के साथ पूछा कि क्या मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि राजीव का इस मित्रता से इतना लगाव क्यों है? इसके पीछे क्या कोई राज है? अमिताभ को टिकट देने के लिए राजीव ने क्यों जिद पकड़ी थी, जबकि फिल्म अभिनेता की काफी लोग सख्त मुखालफत कर रहे थे। क्या राजीव की कोई मजबूरी थी, जिसके कारण वह बच्चन को प्रत्याशी बनाने को मजबूर हो रहे थे? पत्रकार मित्र की ये सब बातें सुनकर मैं कुछ हड़बड़ाया। आज इन सवालों का जवाब देना और कुछ बातों की चर्चा करना चाहूंगा।

प्रधानमंत्रीजी कई कारणों से बिना जरूरत ही कुछ कठिनाइयों में फंस गये हैं। पहले तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप, अरुण नेहरू और कुछ लोगों को खूब उछाला, राजनीतिक गगन में उनकी छवि चमकायी और उनका विश्वास किया। लोग कहते थे कि अरुण सरकार में नंबर दो स्थान पर हैं, जबकि वह काबीना मंत्री भी नहीं थे। वीपी सिंह की भी खूब तूती बोल रही थी। कुछ दिनों बाद कुछेक राजनीतिक कनफुक्कों ने राजीव से यह कहना शुरू किया कि अरुण, 'नेहरू' होने के कारण, अपने को प्रधानमंत्री-पद का दावेदार समझते हैं और आपकी (राजीव की) जगह लेने की फिराक में हैं। यह बात गलत भी हो सकती है और सही भी, मगर राजीव को उनके खिलाफ शक तो हो ही गया। अरुण यह तो सोचते ही थे कि उन्होंने राजीव के प्रधानमंत्री बनने में बड़ी मदद की है और राजीव को उनके कहने पर चलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनकी कई बातें मानी भी। राजीव से लोगों ने यह भी कहा कि विश्वनाथ प्रताप अपनी छवि बनाने में लगे हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अखबारी दुनिया में उनकी हवा बंधती जा रही है। ऐसी हालत में राजीव को राजा के खिलाफ आगाह होना ही पड़ा।

अंदर-अंदर उनमें कुछ मतभेद तो चल ही रहे थे। बच्चन सीधे आदमी लगते तो हैं, मगर हैं नहीं। उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाया। वह राजीव के और भी नजदीक हो गये। इन दोनों ने एक दूसरे का पल्ला कस कर पकड़ा, क्योंकि दोनों मुखतलिफ तरह की मुसीबतों में फंस रहे थे। अमिताभ जानते ही थे कि वह और उनके भाई कैसे काम कर रहे हैं। वित्तमंत्री से उनकी खटपट चल ही रही थी। ऐसी परिस्थिति में जो हुआ, वह अनिवार्य था।

अब एकदम फिर इलाहाबाद के उपचुनाव कि तरफ आ जाइये। राजीव, वीपी सिंह को इस चुनाव में पटक कर यह साबित करना चाहते थे और हैं कि उनके सब आरोप निराधार और झूठे हैं और जनता ने उन्हें हराकर यह साबित कर दिया है। राजा साहब अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता और अखबारों के सहयोग के अश्वमेध के घोड़े पर चढ़कर राजीव के बच्चन को धराशायी करके यह दिखाना चाहते थे कि देश ने सरकार के खिलाफ उनकी सब बातें मान ली हैं और जनता उनके साथ है।

राजीव के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी। वह जानते थे कि वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद के लल्लू, पल्लू प्रत्याशी हलके पड़ेंगे। केवल अमिताभ ही विश्वनाथ को हरा पायेगा। वह कुछ दिन इस बात पर जमे रहे कि टिकट बच्चन को ही दिया जाना चाहिए। कुछ समय बाद उन्हें हकीकत का सामना करना ही पड़ा। कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अमिताभ की दबी जुबान से मुखालफत करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद के कई कांग्रेसियों ने डंके की चोट पर अमिताभ के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सरकारी सूत्रों ने भी घुमा-फिरा कर बताया कि इलाहाबाद में हवा बहुत ज्यादा बच्चन के अनुकूल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि राजीव के दो शुभचिंतक, जानेमाने पत्रकारों ने जोरों से अखबारों में लिखा कि प्रधानमंत्री को अमिताभ को खड़ा करके इस चुनाव को निजी लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीतने से कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं और अमिताभ के हारने से हा-हाकार मच जायेगा। यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को यह बात जमी और उन्होंने किसी दूसरे प्रत्याशी की खोज शुरू कर दी।

कई नेतागण इलाहाबाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजे गये। एनडी तिवारी और सुनील शास्त्री के नामों की भी चर्चा हुई। खूब सोच-विचार के बाद यह फैसला किया गया कि सीधा-सादा इस समय सत्ता से बाहर होने वाला आदरणीय लालबहादुर शास्त्री का बेटा जो काफी दिन इलाहाबाद में रह भी चुका है, चुनाव के लिए ठीक रहेगा। ऐसा करके उन्होंने बड़ी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। अमिताभ को चुनाव लड़ाने में न तो था कोई खास लगाव, न इस मामले में उनकी ओर कोई खास खिंचाव, न थी कोई जिद, न कोई मजबूरी-केवल थी और है एकमात्र राजीव की इच्छा कि वीपी सिंह को चारों खाने चित कर दिया जाये। इतने वाद-विवाद के बाद काफी लोगों को आशाएं दिलाने के बाद, अमिताभ को न लड़ाने में राजीव की जनता की निगाह में कुछ हेठी तो हुई ही। जैसे राजा साहब की हुई है, बार-बार यह कहने के बाद कि वह केवल अमिताभ के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, अब उनके न होते हुए भी खुद लड़ रहे हैं। मगर राजनीति में तो ये धंधे होते ही रहते हैं।

पत्रकार मित्र ने मुझसे यह भी पूछा था कि जब अमिताभ की इतनी बदनामी थी, तो उन्हें और उनके परिवार को प्रधानमंत्री अंडमान व लक्षद्वीप छुट्टी मनाने अपने साथ क्यों ले गये? इस सवाल को राजनीतिक न बनाकर, इसे निजी स्तर पर भी रखकर सोचना चाहिए। कोई बचपन का दोस्त अगर अपने मित्र से उसके साथ छुट्टी मनाने का इशारा करे, तो शरीफ आदमी को 'न' करना कठिन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर राजीव पारिवारिक परंपराओं के कारण शरीफ तो हैं ही और मैं इस बात को दावे से कह भी सकता हूं। यह तो अमिताभ को सोचना था कि उनको साथ ले जाने से राजीव को कितना नुकसान पहुंचेगा। मान लिया कि जाने का निमंत्रण राजीव ने ही दिया, तब भी बच्चन को अपने कंधों पर आरोपों की गठरियों का बोझ देखते हुए, जाने से इनकार करना चाहिए था, यदि वह राजीव के सच्चे मित्र हैं।

मैं यह साफ-साफ कहना चाहता हूं कि बच्चन बंधुओं को अपने साथ ले जाने में राजीव की राजनीतिक भूल तो थी ही, मगर अच्छे व्यक्ति ऐसी गलतियां अकसर कर बैठते हैं। मुझे इस बात पर हैरत है कि राजीव ने निजी मित्रता को राजनीतिक मित्रता से इतनी गहरी तरह क्यों जोड़ दिया है! इससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसी विचित्र मित्रता के बारे में मैंने न तो कहीं पढ़ा है और न सुना ही है। राजीव को यह जानना चाहिए कि निजी ताल्लुकात की आईसक्रीम को राजनीतिक ताल्लुकात की मदिरा से अलग रखना चाहिए। जब वे दोनों मिलाकर घोट दी जाती हैं, तो कभी-कभी एक बेहद नुकसान देनेवाली नशीली काकटेल बन जाती है और उसका पान करने वाले शांतिपूर्ण वातावरण में नागवार तरीके से खट-खट करने लगते हैं।

—पीडी टंडन

उनके बड़े पुत्र हरिकृष्ण शास्त्री भी इलाहाबाद से सांसद चुने जा चुके हैं। इस प्रकार इस सीट पर तीन बार शास्त्री-परिवार चुना जा चुका है। सुनील को प्रत्याशी बनाने में इस आंकड़े ने भी भूमिका निभायी है।

सुनील शास्त्री का कभी स्थानीय राजनीति में दखल नहीं रहा, इसलिए स्थानीय राजनेताओं के लिए वह विवादास्पद नहीं हैं। स्थानीय कांग्रेस को एक करने की दृष्टि से सुनील को अच्छा प्रत्याशी समझा गया। सुनील शास्त्री को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना जरूर आसान काम नहीं था, लेकिन यह काम उनके भाई हरिकृष्ण शास्त्री के माध्यम से कराया गया।

आखिरी समय नाटक कुछ इस प्रकार हुआ। २२ मई को पीएम हाउस से सुनील शास्त्री को (उनके दिल्ली स्थित बड़े भाई के आवास पर) सूचना दी गयी कि रात्रि ११ बजे वह पालम (दिल्ली हवाई अड्डे) पहुंच जायें। उन्हें सीएम के साथ लखनऊ जाना है। शास्त्री को यह भी हिदायत दे दी गयी थी कि उन्हें इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताना है।

रात्रि ११ बजे पीएम हाउस से वीर बहादुर पालम पहुंचे। वह अकेले थे। सुनील हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उन्हें स्टेट प्लेन से लेकर रात्रि १२ बजे वीर बहादुर, लखनऊ आ गये। एक दूसरी कार से उन्होंने सुनील को उनके घर भेज दिया और खुद कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर आ गये।

> **तब तक एक घटना घट चुकी थी। वीर बहादुर ने दिल्ली फोन मिला कर बूटा सिंह से बात की। बूटा सिंह ने उन्हें बताया, "अमिताभ अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। पीएम ने कहा है कि अब अमिताभ नहीं लड़ेंगे, इसलिए सुनील शास्त्री को ही खड़ा किया जाये। सुनील का पर्चा ११ बजे के बजाय ढाई बजे दाखिल कराया जाये।**

कहां, कितने मतदाता

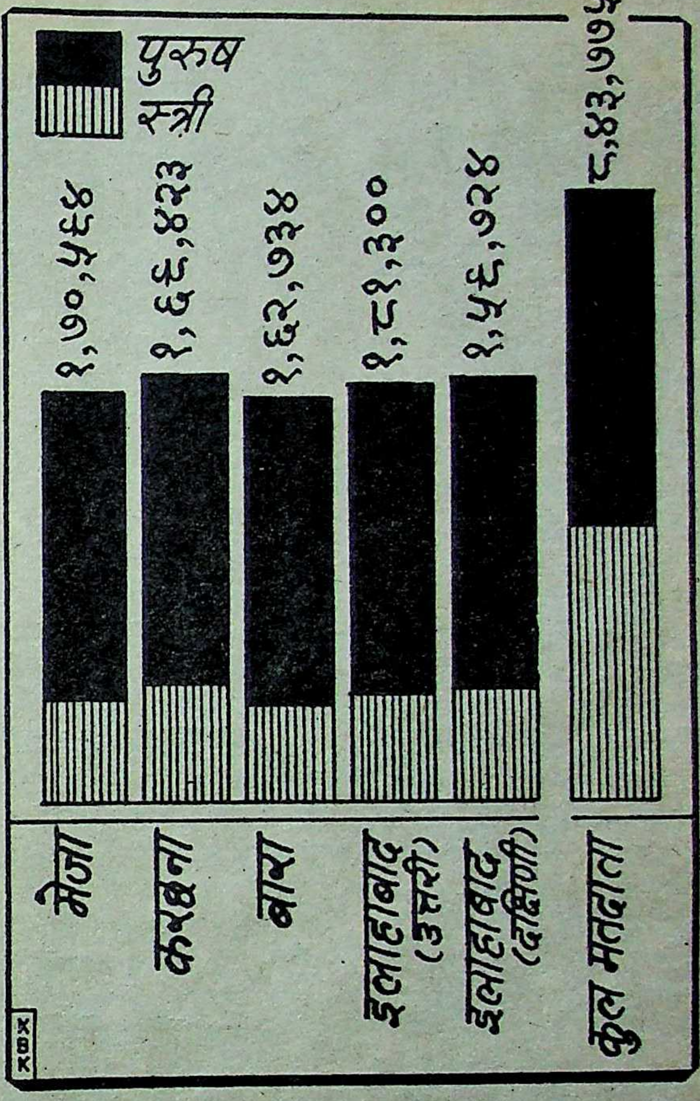

२३ मई की सुबह सर्विस प्लेन से श्रीमती राजेन्द्रकुमारी वाजपेई, अशोक वाजपेई तथा दिल्ली स्थित अमिताभ के एक चहेते पत्रकार लखनऊ पहुंचे। इन सभी की यही जानकारी थी कि अमिताभ ही इलाहाबाद से उम्मीदवार बनाये गये हैं। अमौसी हवाई अड्डे से ये तीनों मुख्यमंत्री के बंगले पर आ गये।

तब तक एक घटना घट चुकी थी। सुबह करीब ८.३० (२३ मई को) वीर बहादुर ने दिल्ली फोन मिला कर बूटासिंह से बात की। बूटासिंह ने उन्हें बताया, "अमिताभ अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। पीएम ने कहा है कि अब अमिताभ नहीं लड़ेंगे, इसलिए सुनील शास्त्री को ही खड़ा किया जाये। सुनील का पर्चा ११ बजे के बजाय ढाई बजे दाखिल कराया जाये।"

"लेकिन, सुनील... "

"ठीक है, जैसा पीएम का आदेश, मैं सुनील को जिताने में पूरी ताकत लगा दूंगा।" इतना कह कर वीर बहादुर ने रिसीवर रख दिया। फिर अपने एक पीए को कुछ गुप्त हिदायतें देकर भेज दिया। पीए, एक सरकारी कार से सुनील शास्त्री के माल एवन्यू स्थित आवास पर पहुंचा तथा उन्हें मुख्यमंत्री का संदेश दे दिया। फिर कुछ ही देर बाद सुनील शास्त्री उक्त पीए के साथ अमौसी हवाई अड्डे जा पहुंचे। तब तक सीएम हाउस से हवाई अड्डे पर फोन पहुंच चुका था। करीब ९.३० बजे सुनील शास्त्री को लेकर स्टेट प्लेन इलाहाबाद रवाना हो गया। (नियमानुसार, स्टेट प्लेन, सुनील शास्त्री को अकेले ले जाने के लिए अधिकृत नहीं था) सवा दस बजे स्टेट प्लेन बमरौली उतरा। जहां से सुनील शास्त्री हाइडिल गेस्ट हाउस पहुंच गये। सीएम के निर्देशानुसार सुनील को वहीं रुकना था। इस प्रकार सुनील शास्त्री को 'हाईजैक' करके ढाई बजे चुनाव मैदान में छोड़ दिया गया। ■

इलाहाबाद की अहमियत

बोफोर्स का जो युद्ध इलाहाबाद में सरेआम लड़ा जाना था वह २३ मई को तीन बजे राजा ने बिना लड़े ही जीत लिया। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने घुटने टेक दिये, तो वीपी सिंह और उनके समर्थक चक्कर में पड़ गये कि अब क्या करें! राजा को पूरा यकीन था कि कांग्रेस-इ हर हालत में अमिताभ बच्चन को ही खड़ा करेगी। वीपी सिंह और उनके समर्थकों के लिए धर्मसंकट की स्थिति इसलिए थी, क्योंकि राजा बार-बार कह रहे थे, "मैं चुनाव तभी लडूंगा, जब कांग्रेस-इ अमिताभ बच्चन को अपना उम्मीदवार बनायेगी।" दरअसल यह कहकर उन्होंने अपना यह इरादा साफ कर देना चाहा कि यह चुनाव वह बोफोर्स के मुद्दे पर जनमत का जायजा लेने के लिए लड़ेंगे। यह एक बेतुका और फालतू ऐलान था और जब बच्चन मैदान से भाग गये, तब राजा दुविधा में पड़ गये। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया था, ताकि वीपी सिंह की जीत का रास्ता साफ रहे।

वीपी सिंह पहले यही चाहते थे कि चुनाव के मैदान से हट जायें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को बेनकाब करने का उनका मकसद पूरा हो चुका था। अमिताभ बच्चन का वीपी सिंह के सामने मैदान में न आने का मकसद समूची दुनिया जान गयी थी कि राजा ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनका सामना करने की हिम्मत कांग्रेस-इ और अमिताभ बच्चन में नहीं है। जनमोर्चा के कईएक सर्मथकों ने तो यहां तक कहा कि अब चुनाव लड़ना वीपी सिंह के लिए अपनी उस बड़ी विजय का महत्व कम करना है जो उन्होंने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वियों पर पायी है।

लेकिन तब तक एक नयी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। उसका तकाजा नया था, उसकी दलील नयी थी। वीपी सिंह कदापि जनमोर्चा के उम्मीदवार नहीं थे। वह लगभग समूचे विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी थे। भाकपा, माकपा, भाजपा, जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस-एस, सबके सब उन्हें समर्थन दे रहे थे। इन सारे दलों के नेताओं ने अपना अधिकार जमाते हुए सवाल उठाया, "अब वीपी सिंह सबकी राय लिये बगैर कोई इकतरफा फैसला कैसे कर सकते हैं? एका की कुछ अपनी बंदिशें होती हैं जो सबको माननी पड़ती हैं।" यह बात राजा के जेहन को छू गयी। अब वह चुनाव लड़ने के लिए विवश थे। आखिर, उन्होंने टेलीफोन से मधु दंडवते को बताया, "विपक्ष ने मुझे जो इतना बड़ा विश्वास दिया है, उसके साथ मैं घात नहीं करूंगा।" इस तरह राजा मैदान में वापस आ गये।

लेकिन अब लड़ाई ही बदल चुकी है। अब दूसरी बातें दांव पर लग गयी हैं। इसे समझने के लिए वीपी सिंह की अहमियत को समझना होगा। वीपी सिंह इस कारण महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वह सबसे बुद्धिमान हैं या सबसे योग्य हैं अथवा विपक्षी नेताओं में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हैं। उनका वास्तविक महत्व यह है कि वह सबसे अधिक विश्वासी बन गये हैं। जनता के अलावा विपक्ष के विभिन्न नेता उन पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं और राजा की व्यक्तिगत खूबियों से उपजा है। मंत्री-पद को लात मारने की उनकी हिम्मत, दोषी लोगों को सामने लाने की उनकी जिद, सरकार की ओर से उन्हें मिली प्रताड़ना आदि ने मिलकर राजा की अहमियत में इजाफा किया है। बेशक वह कोई मसीहा नहीं हैं, उनका महत्व यह है कि वह एकता—विपक्षी एकता यानी इंका के विकल्प के उत्प्रेरक बन गये हैं।

चंद्रशेखर, देवीलाल, एचएन बहुगुणा, रामकृष्ण हेगड़े, अजीत सिंह, मधु दंडवते, भाजपा और भाकपा-माकपा, सबको एक दूसरे की जरूरत है—चाहे वे यह बात खुलकर कहें या न कहें। वीपी सिंह यह जरूरत पूरी करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस बात को सब समझ रहे हैं। इसी कारण इन नेताओं और दलों ने इस बात को महत्व दिया कि वीपी सिंह इलाहाबाद का उपचुनाव जरूर लड़ें, चाहे अमिताभ बच्चन मैदान में आयें या न आयें। इसीलिए कांग्रेस-इ नये जोशखरोश के साथ अपनी सारी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रही है, ताकि वह राजा को हरा दे। इस तरह यह उपचुनाव सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए अस्तित्व का प्रश्न बन गया है।

और कहीं वीपी सिंह जीत गये तो? सिर्फ यही नहीं कि यह घटना विपक्ष के एकजुट होने की प्रक्रिया को एकबारगी तेज कर देगी। यह केंद्र में कांग्रेस-इ सरकार की कब्र खोदने का कारण सिद्ध हो सकती है।

कहीं वीपी सिंह हार गये, तो क्या होगा? यही नहीं कि जनमोर्चा एकबारगी ध्वस्त हो जायेगा, यही नहीं कि राजा का राजनीतिक भविष्य चौपट हो जायेगा, बल्कि अगले आम चुनाव के पहले विरोधी एकता कायम हो जाने की जो एकमात्र संभावना नजर आ रही है, वह समाप्त हो जायेगी। चूंकि इस तथ्य को विपक्ष के अधिकतर नेता जान रहे हैं, इसलिए वे इलाहाबाद उपचुनाव को मात्र एक उपचुनाव नहीं, बल्कि अपनी हस्ती बनाये रखने का आखिरी मौका मान रहे हैं। हार के संहारक नतीजे और अस्तित्व के खतरे ने विपक्ष को अपनी सारी शक्ति लगा देने के लिए मजबूर कर दिया है।

और कहीं वीपी सिंह जीत गये तो? सिर्फ यही नहीं कि यह घटना विपक्ष के एकजुट होने की प्रक्रिया को एकबारगी तेज कर देगी। यह केंद्र में कांग्रेस-इ सरकार की कब्र खोदने का कारण सिद्ध हो सकती है। यह राजीव गांधी की हुकूमत के खातमे की शुरुआत भी साबित हो सकती है। सत्तारूढ़ दल की सारी शक्ति और सरकारी मशीनरी लगी रहने के बावजूद, कहीं वीपी सिंह संसद में पहुंच गये, तो करीब ४०० सांसदों की मनोदशा पर, जो उनके सामने बैठेंगे, जबरदस्त असर पड़ेगा। वीपी सिंह उन्हें रोज याद दिलायेंगे कि उनके राजनीतिक अंत की घड़ी करीब आ गयी है।

कांग्रेस-इ के चरित्र और उसकी मानसिकता को देखते हुए, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। सरकार से जुड़े नेता इस बात को समझते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस-इ वीपी सिंह को इलाहाबाद में हराने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखेगी। उनकी जीत १९९० में होने वाले चुनावों से पहले ही कांग्रेस-इ पर कहर ढा सकती है।

—रजिंदर पुरी

छाया :
प्रदीप चंद्र

अमिताभ बच्चन ने शायद ही किसी ऐसी फिल्म में काम किया हो, जिसमें उतना सस्पेंस रहा हो, जितना उन्होंने २३ मई को इलाहाबाद में पैदा किया। उस दिन इलाहाबाद संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए परचा दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। अमिताभ के चहेते ही नहीं, बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आंखें फाड़े और मुंह बाये यह सोच रहे थे कि वह अब आये...अब आये! लेकिन जिस समय इंतजार और अफवाहों का बवंडर मंडरा रहा था, उस समय अमिताभ बच्चन बम्बई में 'तूफान' को फिल्माने में लगे थे।

जंग का ऐलान : विश्वनाथ प्रताप सिंह नामांकन पत्र भरते हुए और विधायक अनुग्रह नारायण सिंह (दायें)

छाया : वसीमुल हक

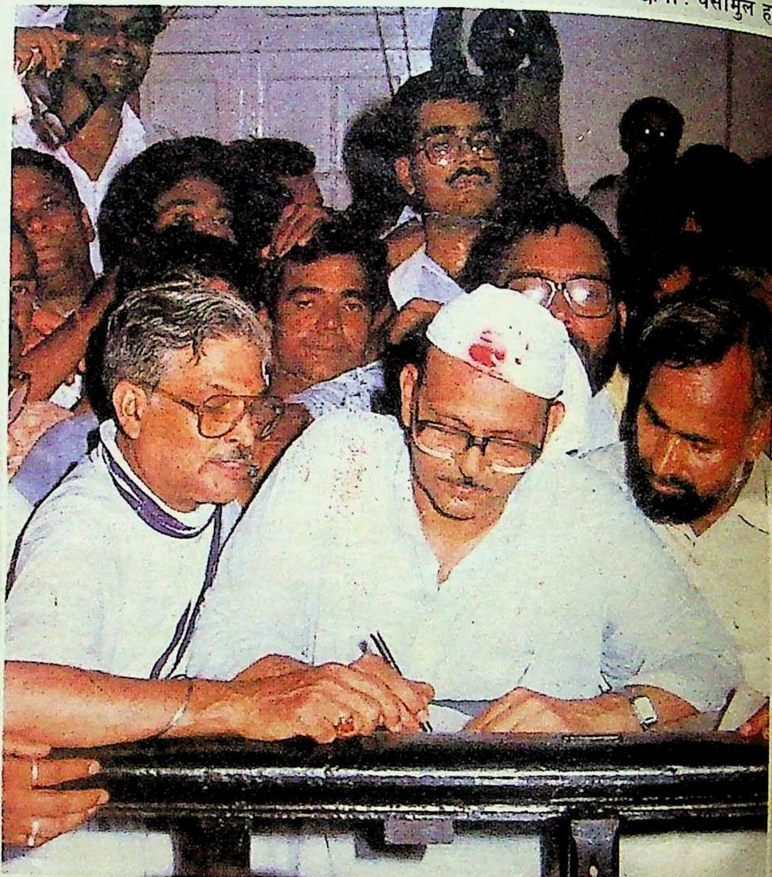

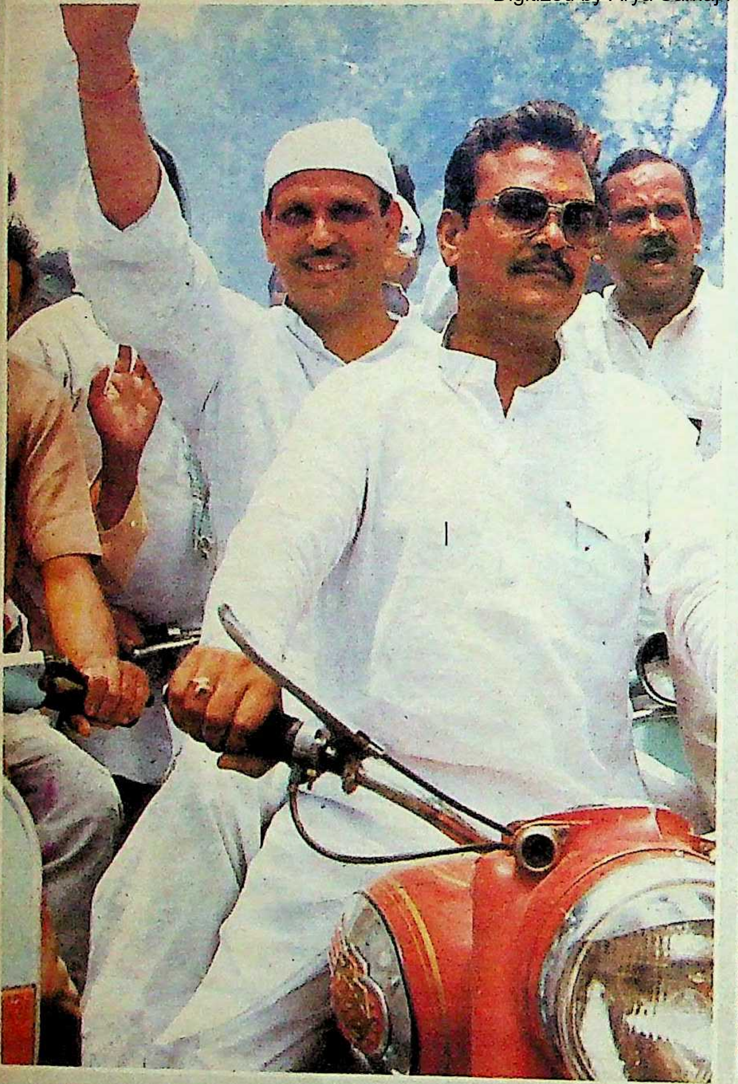

नया प्रयोग : धनशक्ति का मुकाबला जनशक्ति से करने के लिए वीपी सिंह मोटर-कार के बजाय मोटर साइकल पर चुनाव-अभियान के लिए जाते हुए।

छाया : वसीमुल हक

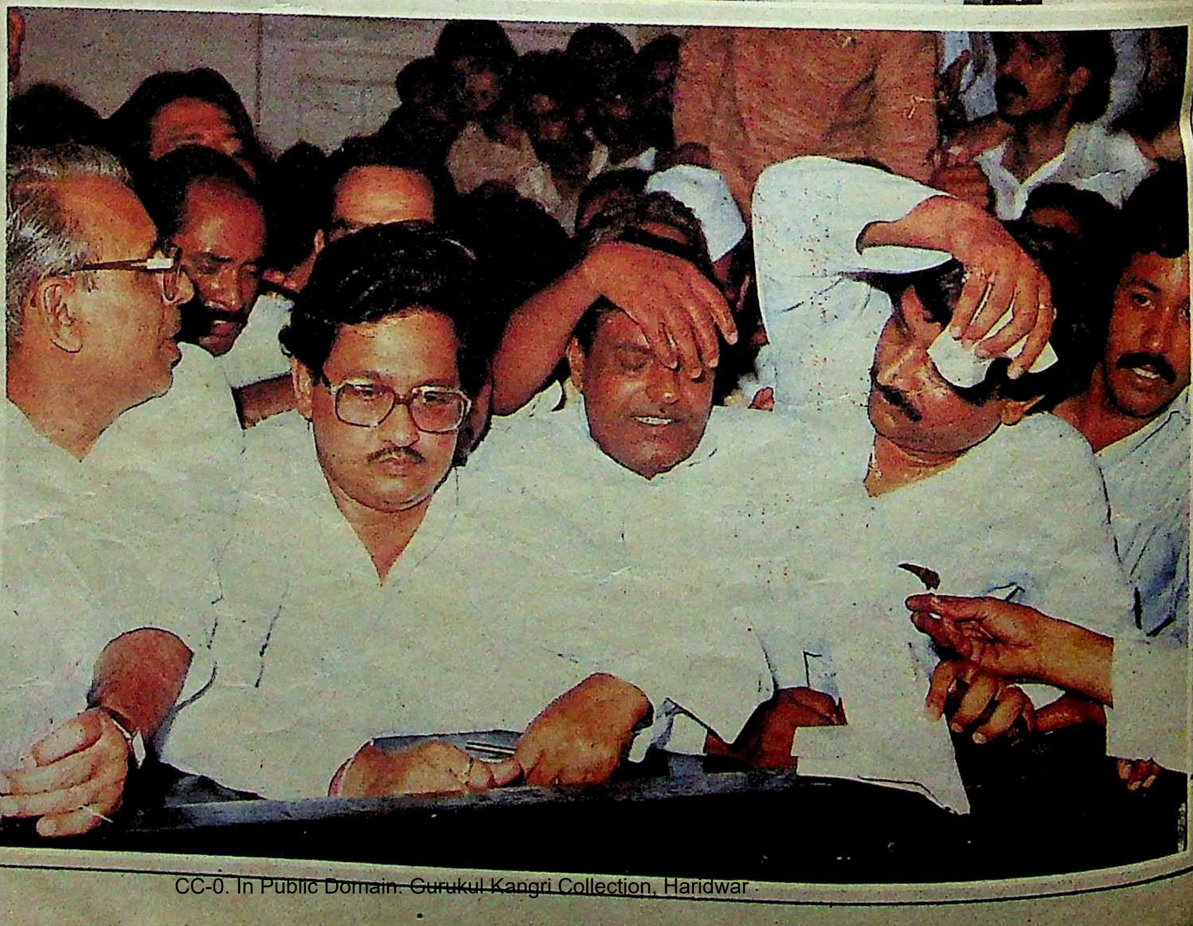

अमिताभ की जगह सुनील शास्त्री : नामांकन पत्र दाखिल करते समय (बायें से), श्याम सूरत उपाध्याय (मंत्री), सुनील शास्त्री, वीर बहादुर सिंह (मुख्यमंत्री) और प्रमोद तिवारी (मंत्री)

छाया : वसीमुल हक

हुए और
ह (दायें)
सीमुल हक

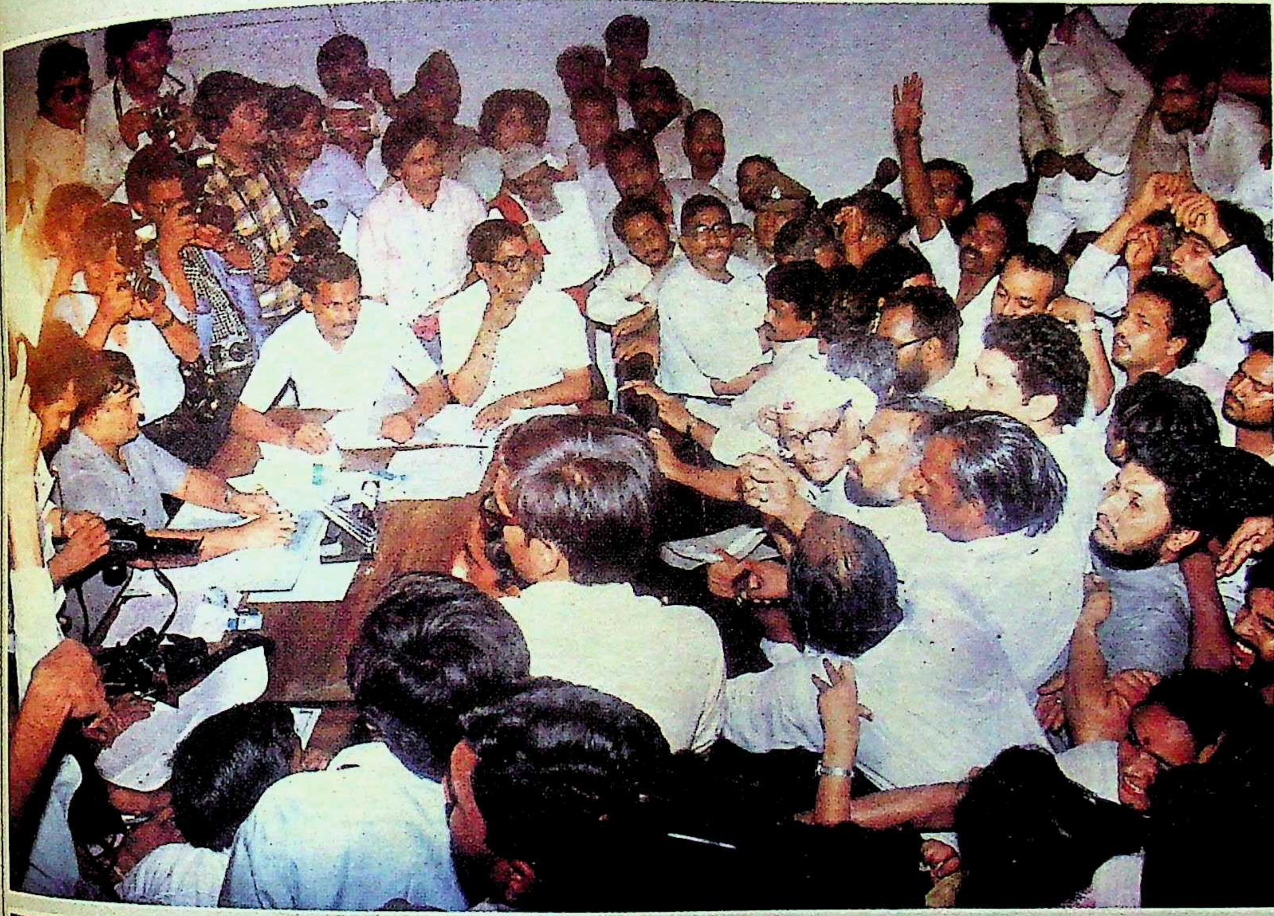

ऐतिहासिक अवसर : विश्वनाथ प्रताप सिंह के नामांकन के समय का विहंगम दृश्य

छाया : राजेंद्र कुमार

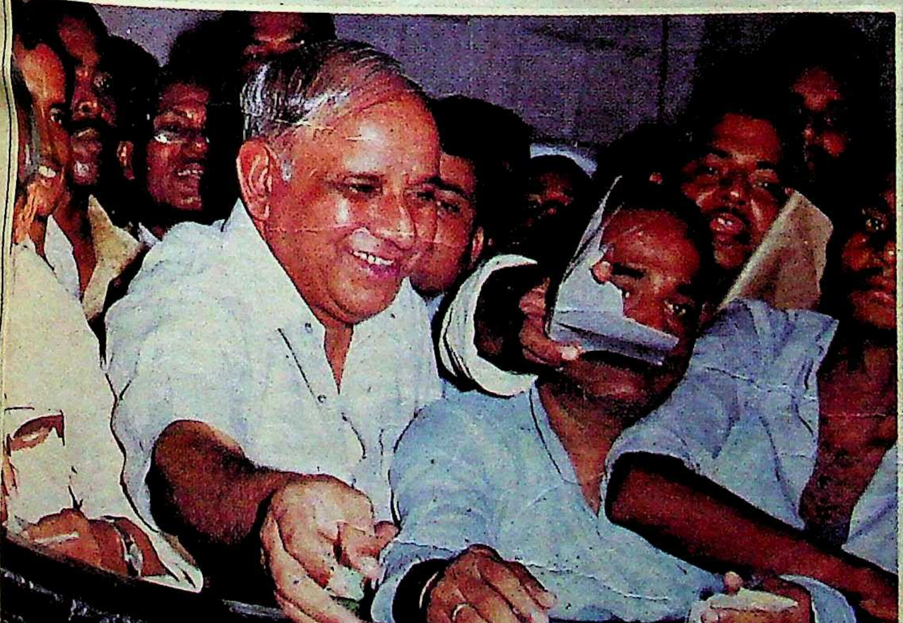

तीसरा कोण ? : बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कांशीराम चुनावी जंग में पर्चा दाखिल करते हुए।

छाया : वसीमुल हक

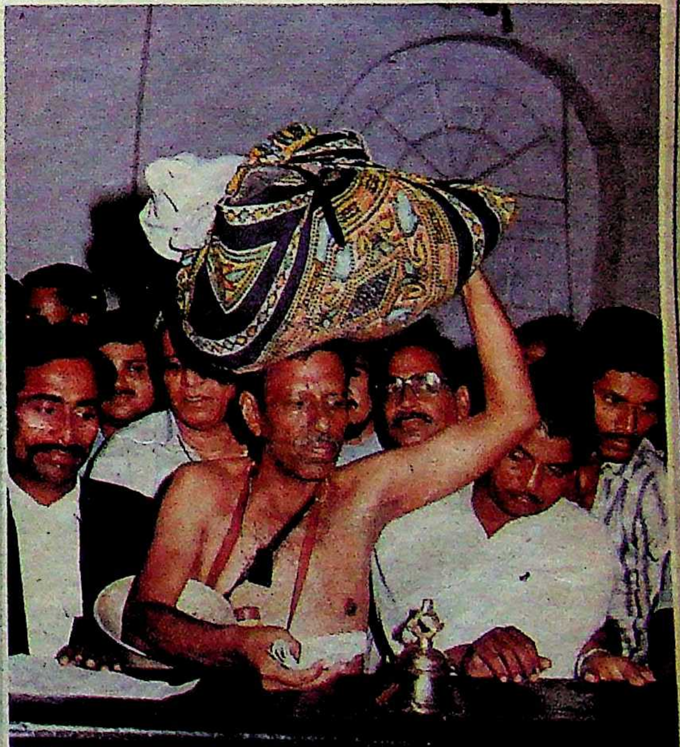

सदाबहार : हर चुनाव में प्रत्याशी बननेवाले धरती पकड़

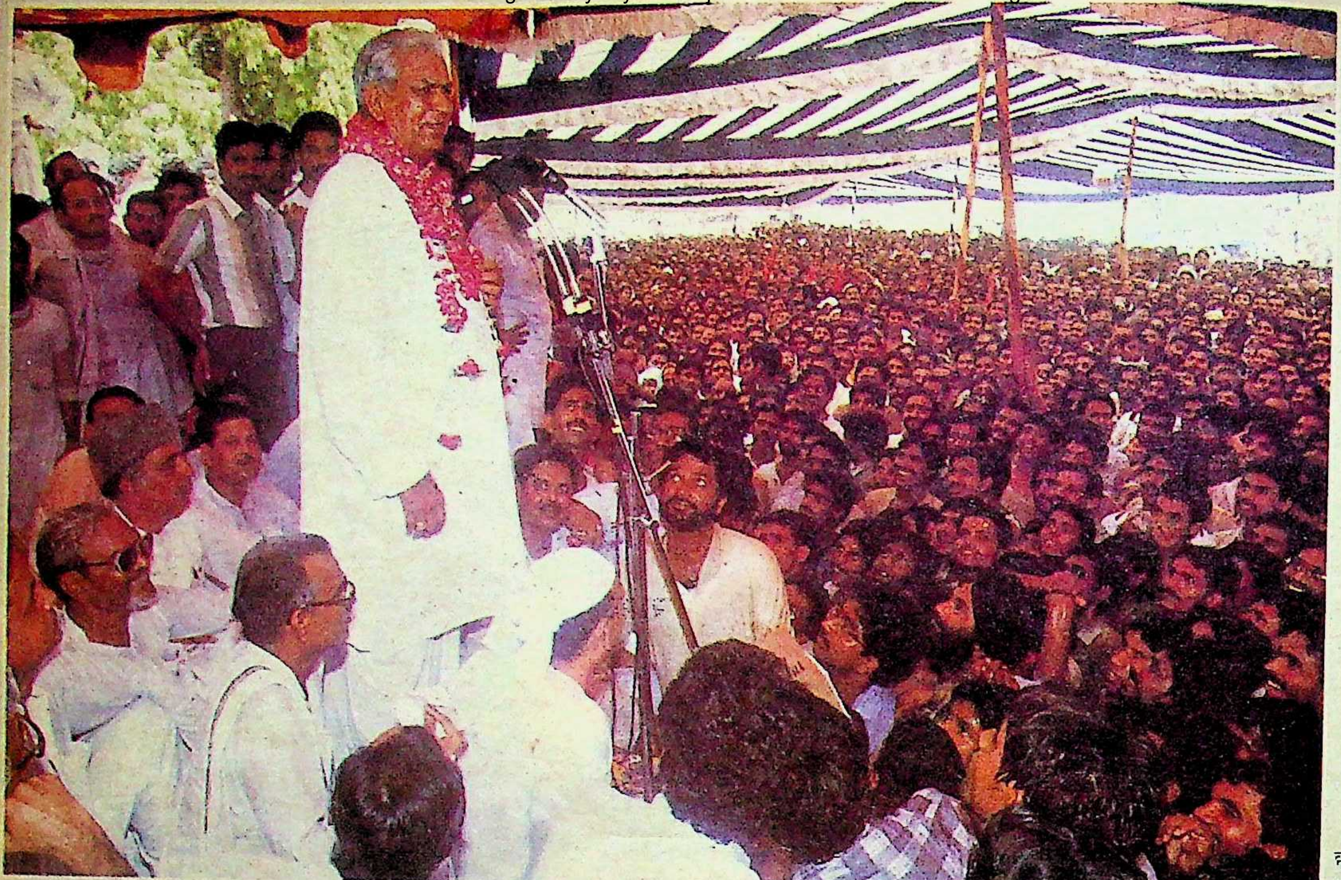

छाया :
वसीमुल हक

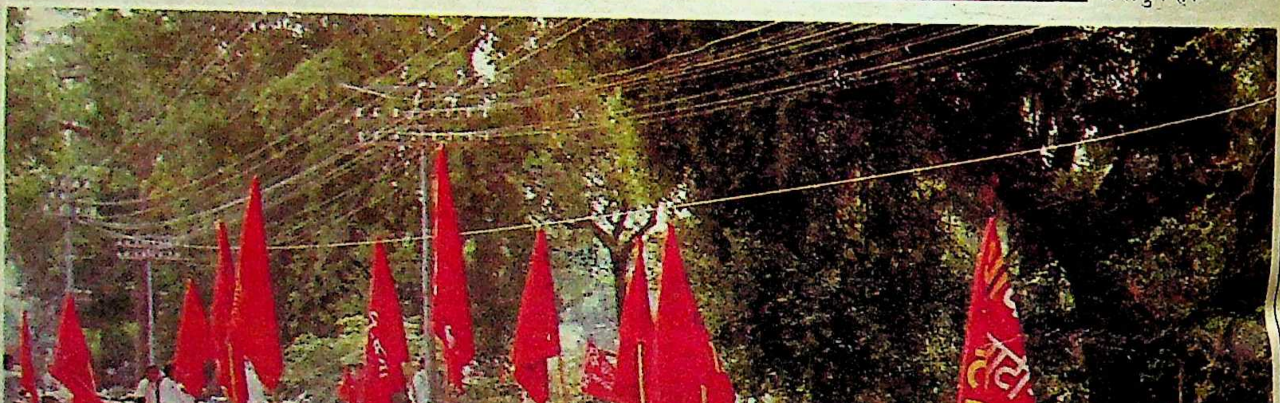

विपक्ष का भविष्य दांव पर : वीपी सिंह के समर्थन में २३ मई को इलाहाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल (ऊपर)।

अभियान के लिए तैयार : वीपी सिंह के कार्यकर्ताओं के झण्डे लगे वाहन।

राजस्थान उपचुनाव

इस बार लड़ाई कांटे की

शंकर लाल (कांग्रेस-इ)

गुमानमल लोढ़ा (भाजपा)

सुखलाल सैणचा (लोकदल-ब)

प्रदेश के पाली संसदीय क्षेत्र और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में बंटा हुआ विपक्ष और कांग्रेस-इ के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। पाली में १६ जून को होने वाले इस चुनाव में पूर्व विधायक शंकरलाल कांग्रेस-इ के उम्मीदवार हैं, वहीं भाजपा ने पूर्व न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में भाजपा और लोकदल-ब का हुआ मेल-मिलाप राजस्थान में नहीं चल सका है। पाली में लोकदल-ब के उम्मीदवार सुखलाल सैणचा मैदान में बरकरार हैं।

पाली के दिवंगत सांसद मूलचंद डागा चूंकि कांग्रेस-इ के सांसद थे, इसलिए कांग्रेस-इ का उम्मीदवार बेहतर स्थिति में समझा जा रहा है। वैसे दिवंगत सांसद पाली से निर्वाचित वर्तमान विधायक कुमारी पुष्पा जैन से मात्र ३५ हजार मतों से विजयी हुए थे। विजय की यह बढ़त प्रदेश की २५ ससदीय सीटों में सबसे कम थी। उम्मीद की जा रही थी कि दिवंगत सांसद के सम्मान को भुनानें के लिए कांग्रेस-इ का टिकट उनके पुत्र डाक्टर मृदुल डागा को दिया जायेगा। विरासत के पारितोषिक की अपेक्षा से दिल्ली में निवास करने वाले मृदुल डागा अंत तक पाली में जमे हुए थे। पर टिकट हासिल हुआ—पाली शहर के पूर्व विधायक शंकरलाल को, जिन्हें केंद्रीय गृहमंत्री बूटासिंह का समर्थन हासिल था।

एकता का नाटक: संसदीय क्षेत्र की इस सीट के लिए विपक्ष ने एकता बनाये रखने का नाटक दिखावे के लिए किया। भाजपा, जनता पार्टी और लोकदल-ब के नेताओं की वार्ता भी दिल्ली में हुई, पर भाजपा के नेता भैंरोंसिह शेखावत को शिकस्त देने के लिए एक प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी और नाथूराम मिर्धा अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे। भैंरोंसिह शेखावत यह मान कर चल रहे थे कि चूंकि भाजपा विधायिका कुमारी पुष्पा जैन संसदीय चुनावों के पराजितों में श्रेष्ठ थीं, इसलिए चुनाव लड़ने का पहला अधिकार विपक्ष की ओर से उनको था। कुमारी पुष्पा जैन की उम्मीदवारी को भाजपा नेताओं ने अपनी गुटबंदी के कारण रद्द करते हुए गौहाटी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं राज्यसभा के चुनावों के दौरान पैदा हुई विपक्ष की फूट ने अपना रंग दिखा दिया। राज्यसभा के चुनावों में जनता पार्टी और लोकदल-ब के संयुक्त उम्मीदवार कमल मोरारका के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश प्रसाद माथुर को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। इससे नाराज जपा और लोकदल-ब के नेता अब भाजपा को सबक सिखाने के लिए मैदान में हैं। नतीजा यह हुआ कि नाम वापस लेने के बाद मैदान में जनता पार्टी और लोकदल-ब के उम्मीदवार के रूप में लोकदल के सुखलाल सैणचा मैदान में हैं, वहीं भाजपा के गुमानमल लोढ़ा तथा कांग्रेस-इ के शंकरलाल छह निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मैदान में हैं। भाजपा को आशा की किरण अपने प्रत्याशी गुमानमल लोढ़ा के चमत्कारी नारे में नजर आ रही है।

लोढ़ा का मरुधर प्रदेश: जोधपुर निवासी श्री लोढ़ा ने न्यायाधीश बनने से पूर्व १९७७-७८ में जोधपुर तथा उसके आसपास के जिलों को जोड़ कर 'मरुधर-प्रदेश' बनाने का विचार व्यक्त किया था। उस वक्त यह बात जनता पार्टी के शासन में आ जाने से तूल नहीं पकड़ सकी, पर वर्तमान चुनावों में यह रुचिकर नारा बन सकता है। श्री लोढ़ा का मानना है कि जिस तरह पंजाब से अलग हरियाणा ने चहुंमुखी प्रगति की है उसी तरह 'मरुधर-प्रदेश' अलग से बन जाने पर रेगिस्तानी इलाके की भारी उन्नति हो सकती है। श्री लोढ़ा ने आपातकाल की समाप्ति के तुरंत बाद अपनी कल्पना के मरुधर-प्रदेश का एक नक्शा भी प्रचारित किया था। लोग आंदोलन के लिए प्रेरित भी हुए थे, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भैंरोंसिह शेखावत ने लोढ़ा को खामोश करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनवा दिया था। अब पाली उप चुनाव में श्री लोढ़ा मरुधर प्रदेश का नारा देकर चमत्कार कर सकते हैं। बहरहाल, वोट-बैंक जिस तरह से कांग्रेस-इ के पक्ष में है, उसके रहते लोढ़ा अपने नारे से कितने कारगर होते हैं, देखने की बात है।

पाली में विपक्ष के विवाद ने खेतड़ी विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस-इ को बेहतर स्थिति में ला दिया है। पाली की तरह ही खेतड़ी में भी कांग्रेस-इ और भाजपा के प्रत्याशियों के विरुद्ध लोकदल-ब के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह को जनता पार्टी ने अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया। गुर्जर बाहुल्य इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस-इ ने अपना उम्मीदवार डा० जितेन्द्र को बनाया है, जबकि भाजपा ने हजारी लाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। खेतड़ी विधानसभा सीट पर पहले भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस-इ का प्रत्याशी यहां केवल बाईस सौ मतों से पराजित हुआ था। वैसे १९७७, १९८० व १९८५ के चुनावों में यहां से भाजपा के दिवंगत विधायक मालाराम गुर्जर निर्वाचित होते रहे हैं। जाति का समीकरण इस निर्वाचन क्षेत्र में काफी प्रभावी रहा है। एक लाख पांच हजार मतदाताओं में से ४० हजार के लगभग यहां गुर्जर हैं। आठ से दस हजार के लगभग ब्राह्मण, छह हजार वैश्य, सात हजार माली, छह हजार जाट, तीन हजार अहीर व बीस हजार हरिजन हैं। इनमें गुर्जर अपनी एकता के कारण हमेशा निर्णायक होते हैं। पर इस बार जातियों का विभाजन सत्ताधारी दल अपने पक्ष में कर पायेगा, इसकी सम्भावना विपक्ष के विभाजन से स्पष्ट हो रही है।

कुल मिलाकर इस उपचुनाव में सत्ताधारी दल की पराजय जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के लिए संकट उपस्थित करेगी, वहीं विपक्ष की हार विपक्ष के नेता भैंरोंसिह शेखावत के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी होगी।

—ओम सैनी

मप्र-खरसिया उपचुनाव

अर्जुन सिंह : मुकाबले की टक्कर

विजय आसान नहीं : अर्जुन सिंह

विजयी होने का दृढ़निश्चय : दिलीप सिंह जूदेव

मध्य प्रदेश में उपचुनाव हालांकि तीन स्थानों—लश्कर पूर्व, गोहद और खरसिया में हो रहे हैं, किंतु लोगों की नजरें खरसिया में अटकी हुई हैं, जहां से मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह अपनी परंपरागत सीट छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो यह दूसरा प्रसंग है, जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री दूसरे अंचल में जाकर चुनावी दंगल लड़ रहा है। पूर्वमुख्यमंत्री व लौह पुरुष पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने लगभग दो दशक पूर्व महाकोशल छोड़ छत्तीसगढ़ में कसडोल से उपचुनाव लड़ा था और अब उन्हीं के पट्ट-शिष्य व आधुनिक चाणक्य मानेजाने वाले अर्जुनसिंह विंध्य छोड़कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अभेद्य गढ़ खरसिया से चुनाव लड़ रहे हैं।

उपचुनावों के लिए इंका के अधिकृत प्रत्याशियों के चयन की बैठक यद्यपि २० मई को भोपाल में हुई, किंतु अर्जुनसिंह ने दो दिन पूर्व १८ मई को ही रायगढ़ जाकर कलेक्टर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। बताते हैं कि ऐसा उन्होंने उज्जैन स्थित अपने गुरु मौनी बाबा के इस आशय के परामर्श पर किया कि अठारह मई को वार और नक्षत्र मिलाकर अमृत योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन सर्वसिद्धयोग भी था। लेकिन बताया जाता है कि उस दिन उनके लिए दो अपशकुन हो गये। एक, तो उनकी कार से एक बिल्ली दबकर मर गयी और दूसरे उसी दिन उनकी पहली चुनाव सभा में ही आये तूफान से पंडाल उखड़ गया और छह लोग घायल हो गये। ज्योतिषियों की सलाह पर अर्जुन सिंह ने २३ मई को फिर से रायगढ़ कलेक्ट्रेट में एक और नामांकन पत्र भरा।

खरसिया में अर्जुनसिंह का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह जूदेव से है। दोनों प्रतिद्वंद्वियों में एक अद्भुत साम्य यह है कि दोनों ही सामंती कुल के हैं। दूसरे, दोनों की धार्मिक अनुष्ठानों, तंत्र-मंत्र आदि में गहन रुचि है। अघोरपंथी कीनाराम की परंपरा के औघड़ आचार्य श्रीराम का आशीर्वाद दिलीपसिंह जूदेव को भी प्राप्त है और जशपुर में उनका आश्रम भी है। उनके आश्रम में मत्था टेकने अर्जुनसिंह से लेकर चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई तक पहुंच चुके हैं।

रणनीति : जनमोर्चे के नेता विद्याचरण शुक्ल खरसिया का दौरा कर वहां विपक्ष की रणभेरी फूंकने में अग्रणी अवश्य रहे हैं, किंतु उनकी यह युक्ति विफल रही है कि दिलीपसिंह भाजपा के चुनाव चिन्ह के बजाय स्वतंत्र चिन्ह लेकर चुनाव लड़ें। विद्याचरण चाहते थे कि दिलीप्सिंह भाजपा के बजाय सर्वसम्मत विपक्षी प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ें, मगर भाजपा के कैलाश जोशी ने उनका आग्रह ठुकरा कर उम्मीद जताई कि सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। भाजपा ने लश्कर और गोहद के बजाय अपनी ताकत खरसिया में अधिक झोंकने का फैसला किया है। तैयार रणनीति के अनुसार छत्तीसगढ़ और विंध्य के अधिकांश नेता व कार्यकर्ता खरसिया पहुंचेंगे, जबकि मध्यभारत व महाकोशल के लोग गोहद व लश्कर को कूच करेंगे।

अर्जुनसिंह ने जब दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी उनके विश्वस्त सिपहसालार व सिपाही मध्यप्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे। इसकी पुनरावृत्ति खरसिया में हो रही है। हालांकि, उपचुनाव ग्वालियर में लश्कर व पड़ोस में गोहद में भी है, किंतु भगवानसिंह यादव सरीखे नेता ग्वालियर छोड़ खरसिया पहुंच गये हैं। एक तो खरसिया यूं भी कांग्रेस की 'सुरक्षित मांद' है, दूसरे वहां से अर्जुनसिंह जैसा मंजा व कढ़ा हुआ राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेसी शिविर में कयास इस बात का है कि अर्जुनसिंह कितने मतों से जीतते हैं? उनके समर्थकों का दावा है कि सिंह कीर्तिमान मतों से विजयी होंगे। उनके समर्थकों की कोशिश भी यही है कि सिंह रेकार्ड-मतों से जीतें। इसके विपरीत भाजपा नेता [illegible] करते हैं। स्थानीय नेताओं से लेकर लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी व सुंदरलाल पटवा भी कहते हैं कि हम सिंह को कड़ी टक्कर देंगे! बिलासपुर के पूर्व महापौर व जनमोर्चे के नेता अशोक राव कहते हैं, "अर्जुनसिंह के लिये जीत उतनी सरल नहीं है, जितनी कि वह सोच रहे हैं। धरती-पुत्रों के लिये यह एक चुनौती है कि वे एक बाहरी व्यक्ति को कितना स्वीकार करते हैं?"

खरसिया ही नहीं, गोहद और लश्कर में भी इंका के पास साधनों की कमी नहीं है। अनेक इंका नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए खरसिया का उपचुनाव कुंवर साहब के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर बन गया है। भक्ति-प्रदर्शन का यह मौका वे किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहते हैं। खरसिया में इंका के चुनाव प्रचार की बागडोर लक्ष्मी प्रसाद पटेल के हाथों में है। यह सीट श्री पटेल के इस्तीफे से ही रिक्त हुई है। पहले यह माना जा रहा था कि सिंह प्रचार की कमान जगतपाल सिंह के हाथों में सौंप सकते हैं, किंतु जगतपाल के बजाय पटेल को चुनकर इंका के हित में समझदारी का काम किया गया है। श्री पटेल के कतिपय स्थानीय नेताओं से संबंध खराब जरूर थे, किंतु अर्जुनसिंह के खड़े होने से स्थानीय नेताओं का पारस्परिक मनोमालिन्य दब गया है। समझा जाता है कि जगतपाल को प्रचार की कमान इस कारण नहीं थमायी गयी है, क्योंकि उनकी आम जनता में छवि कतई उज्ज्वल नहीं है।

कुछ साल पहले तक इस अंचल में प्रचुर वन थे, मगर पिछले सालों में जंगल चोरों के हाथों वनों का निर्ममता से सफाया हुआ है। यह कटु सत्य है कि जंगल चोरों को रायगढ़ के कुछ आला इंका नेताओं का प्रश्रय प्राप्त है। जातीय दृष्टि से खरसिया में पिछड़ों व आदिवासियों का बहुमत है। गोंड, तंवर एवं कंवर आदिवासी जहां शोषित एवं विपन्न हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग में समाविष्ट अघरिया आदिवासी काफी संपन्न व समृद्ध जोतों के मालिक हैं। क्षेत्र में लगभग २२ हजार अघरिया वोट हैं। रायगढ़ जिला

भाजपा के अध्यक्ष डा० शक्रजीत नायक को इंका में लाने का उपक्रम वस्तुत: अघरिया मतों को थोक में बटोरने के प्रयोजन से ही हुआ था। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि अग्रवालों व अघरियों के काफी वोट दिलीप सिंह जूदेव को मिलेंगे। आदिवासियों के बीच बैठकर उन्हीं की बोली में बतियाने और उनके साथ रूखा-सूखा खाने के स्वभाव और अपनी छवि के कारण जूदेव इंका के परंपरागत वोट-बैंक-आदिवासी वोटों में भी सेंध लगा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि लंगोटी पहने धनुर्धारी पहाड़ी कोरवा आदिवासियों का जत्था जूदेव के साथ बतौर अंगरक्षक चलता है। विकास की किरणों से कोसों दूर ये आदिवासी अपने इस राजा के लिए मरने-मारने को तैयार रहते हैं। जशपुर नगरपालिका व रायगढ़ जिले में तीन सीटों पर भाजपा को जिताने का श्रेय भी जूदेव को प्राप्त है। अन्य विपक्षी दलों के अलावा उन्हें कल्याण आश्रम का भी संबल है, किंतु ईसाई मिशनरियों को वह फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। खरसिया में जो थोड़े बहुत ईसाई वोट हैं, वे एकमुश्त इंका को जायेंगे। इस बात पर प्राय: सभी एकमत हैं कि इंका के परंपरागत दुर्ग खरसिया में अर्जुनसिंह का पलड़ा भारी है, किंतु जूदेव के मैदान में आने से चुनाव-संग्राम एकतरफा होने से बच गया है। यही कारण है कि खरसिया के नतीजे में आम लोगों के साथ-साथ राजनीतिक पंडितों की भी दिलचस्पी बढ़ गयी है।

—सुधीर सक्सेना, खरसिया से

गोहद और लश्कर

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

आगामी १६ जून को खरसिया के साथ-साथ गोहद और लश्कर (पूर्व) में भी मतदान होगा। इन दोनों ही स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में इंदिरा कांग्रेस से बाजी मारी है। भाजपा ने गोहद से श्रीराम जाटव और लश्कर (पूर्व) से भाऊ साहब पोतनीस को खड़ा किया है। इन दोनों का मुकाबला इंका के क्रमश: सोपत सिंह और डा० हरीश गोयल से होगा। लश्कर पूर्व में उपचुनाव भाजपा विधायक गंगाराम बांदिल के देहांत के फलस्वरूप हो रहा है। (स्व०) बांदिल ने १९८० में चंद्रमोहन नागोरी और १९८५ में श्रीमती रश्मि परिहार को हराया था। यहां से भाजपा टिकट के लिए इस दफा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शीतला सहाय ने भी चेष्टा की, परंतु भाजपा नेतृत्व ने ग्वालियर के पूर्व महापौर पोतनीस को काफी सोच-विचार कर मैदान में उतारने का फैसला किया। खरसिया, गोहद और लश्कर में भाजपा की सबसे अच्छी स्थिति लश्कर पूर्व में ही मानी जा रही है। इंका टिकट के लिए नागोरी से लेकर श्रीमती परिहार तक ने काफी भागदौड़ की। टिकट न मिलने से उनमें हताशा का संचार होना स्वाभाविक है। भाजपा उम्मीदवार को इंका की भितरघात और गुटबाजी का भी फायदा मिल सकता है। वैसे, यहां जातीय दृष्टि से बनियों की बहुतायत है। करीब २० हजार बनियों के अलावा लगभग १८ हजार हरिजन, १६ हजार ब्राह्मण, ८ हजार राजपूत, ६ हजार महाराष्ट्रियन एवं ८ हजार पंजाबी मतदाता हैं। क्षेत्र में सात-आठ हजार मुस्लिम मत भी हैं, जो इंका की झोली में जायेंगे।

गोहद की सीट हालांकि सिंधिया के इलाके में है, किंतु यहां से आलाकमान ने सोपत सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, जो अर्जुन-खेमे के हैं। गोहद में प्रचार की कमान भी सांसद सुभाष यादव के हाथों में है। इसी खेमे के दाऊ हनुमंत सिंह भी यहां डेरा डाले पड़े हैं। गोहद में इंका को जाटव वोटों का विशेष आसरा था, लेकिन भाजपा द्वारा पूर्वविधायक व हरिजन नेता श्रीराम जाटव को मैदान में उतार देने से जाटव मतों का विभाजन होगा। सनाढ्य, ऋषीश्वर एवं भारद्वाज ब्राह्मणों में से, इंका सूत्रों के अनुसार, सनाढ्यों व ऋषीश्वरों के वोट इंका को मिलेंगे। राजपूतों में यहां तोमरों की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा कुशवाहा व गूजर भी हैं। चुनावी बयार से आभास होता है कि यहां हारजीत अधिक मतों के अंतर से नहीं होगी। भाजपा की रणनीति यह है कि अर्जुनसिंह को अधिक-से-अधिक खरसिया में घेरकर रखा जाये, ताकि वह गोहद और लश्कर पूर्व को समय न दे सकें। अर्जुनसिंह को परेशानी में डालने के लिए जो प्रोग्राम तय किया गया है, उसके अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी तीन दिन खरसिया में बितायेंगे। लालकृष्ण आडवाणी व जगन्नाथराव जोशी दो रोज के लिए वहां जायेंगे और सुंदरलाल पटवा ज्यादा समय खरसिया में गुजारेंगे। प्रतिपक्ष के नेता व पूर्वमुख्यमंत्री कैलाश जोशी गोहद व लश्कर में भाजपा के प्रचार का संचालन करेंगे और प्रचार में राजमाता विजयराजे सिंधिया भी शिरकत करेंगी। दूसरी ओर, खरसिया में लक्ष्मी पटेल की सक्रियता के बावजूद सूत्र-संचालन सही मायनों में अर्जुनसिंह के सुपुत्र अजय सिंह के हाथों में है।

छपरौली और टांडा

विपक्ष का पलड़ा भारी

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ टांडा (फैजाबाद) और छपरौली (मेरठ) की विधानसभा भी इंका और विपक्ष के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। टांडा की सीट वापस पाने के लिए जहां इंका ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है वहीं अपने गढ़ छपरौली में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अजीत सिंह बेचैन है।

ऐन मौके पर इन दोनों सीटों के लिए विपक्ष ने जिस तरह की एकता दिखायी है, उससे अब यह लगने लगा है कि अगर वीरबहादुर ने कोई करिश्मा न किया तो ये दोनों सीटें भी विपक्ष की ही झोली में जायेंगी। शायद यही वजह है कि वीरबहादुर सिंह ने इन दोनों स्थानों पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के चुनाव संचालन का दायित्व उन्होंने अपने सांसद दोस्त बलराम सिंह यादव के साथ-साथ सीताराम केसरी को सौंप दिया है।

टांडा में कौन जीतेगा : उम्मीदवार के चयन से असंतुष्ट इंकाइयों को अगर जल्द ही पटाया नहीं गया, तो यह निश्चित है कि इंका प्रत्याशी मुख्तार अहमद किदवई अपनी ही पार्टी के लोगों की दगाबाजी का शिकार हों जायेंगे। वर्ष १९८५ के विधानसभा चुनाव में इस सीट से इंका के वयोवृद्ध नेता जयराम वर्मा (अब स्वर्गीय) २६,२७१ मत प्राप्त कर विजयी हुए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी जनता पार्टी के गोपीनाथ वर्मा मात्र पांच हजार मतों से हारे थे। इसके पूर्व १९८० में यह सीट गोपीनाथ वर्मा के कब्जे में थी। जनता शासन काल में हुए विधानसभा चुनाव (१९७७) में इंका के जयराम वर्मा, मोहम्मद हफीज (जनता) से हारे थे।

प्रतिष्ठा की इस सीट पर इंका ने ८२ वर्षीय वृद्ध मुख्तार अहमद किदवई को उम्मीदवार बनाया है। वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्हें टिकट दिलाने में फैजाबाद के सांसद निर्मल खत्री ने प्रमुख भूमिका निभायी है, लेकिन खत्री उन्हें चुनाव भी जिता सकेगें, यह समय बतायेगा।

दरअसल, इंका के टिकट के लिए पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेटली, स्वर्गीय जयराम वर्मा के नाती राकेश वर्मा और हथकरघा राज्यमंत्री निसार अहमद अंसारी भी अपने-अपने स्तर से प्रयत्नशील

थे। अकबरपुर के सांसद रामप्यारे सुमन तथा इंका समर्थक निर्दलीय विधायक शेर बहादुर सिंह, प्रियदर्शी जेटली को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि कृषिमंत्री नरेंन्द्रसिंह, जयराम वर्मा के नाती के नाती राकेश को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में थे, क्योंकि जयराम वर्मा के निधन से ही इस रिक्त सीट का चुनाव हो रहा है। इंका का ही एक गुट राज्यमंत्री निसार अहमद अंसारी को लड़ाने का पक्षधर था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी में मुख्तार अहमद किदवई को टिकट दे दिया। नतीजतन इंका के अन्दर ही एक गुट अधिकृत प्रत्याशी का विरोधी बन गया, लेकिन विपक्ष में भी कम उठापटक नहीं हुई।

जनता पार्टी ने गोपीनाथ वर्मा को टिकट दिया, उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया, लेकिन ऐन मौके पर वह पार्टी छोड़कर लोकदल-ब के खेमे में कूद गये। अंततः जनता पार्टी को निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हरिराम वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। बाद में विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त प्रत्याशी लड़ाये जाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के तहत यह समझौता हुआ कि लोकदल-ब टांडा से प्रत्याशी लड़ाये और जनता पार्टी, छपरौली (मेरठ) की सीट पर भाग्य आजमाये। इसी कारण जनतापार्टी के हरिराम वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया। इंका और लोकदल-ब के उम्मीदवारों के साथ जो १७ प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें बीएसपी के करमजीत और मुस्लिम मजलिस के अब्दुल मजीद अंसारी भी हैं।

एक लाख अड़सठ हजार से अधिक मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या ४० हजार कुर्मी मतदाताओं की है। इसके बाद मुस्लिम (३५ हजार), हरिजन (३० हजार), यादव (२० हजार), ब्राह्मण (१० हजार), ठाकुर (६ हजार) हैं। शहरी क्षेत्र के ७० प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। जिनमें अधिकांश बुनकर हैं। बुनकर इन दिनों प्रदेश सरकार से काफी रुष्ट हैं। सूत का दाम घटाने, उत्पादित वस्त्रों की खपत बढ़ाने तथा सरकार द्वारा खरीदे गये वस्त्रों के बकाया धन का शीघ्र भुगतान किये जाने की मांग को लेकर, जहां बुनकर काफी समय से आन्दोलित हैं, वहीं बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर मुसलमान, इंका से सख्त नाराज हैं।

अयोध्या से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद खास तौर से चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। भारतीय जनतापार्टी और विश्व हिन्दू परिषद ने जहां जन्मभूमि समर्थक प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है, वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मुस्लिम मजलिस के अब्दुल मजीद अंसारी को जिताने की अपील की है। जाहिर है, मुस्लिम मजलिस का उम्मीदवार, इंका को ही नुकसान पहुंचायेगा। अगर, यह चुनाव, हिंदू-मुसलमान के आधार पर लड़ा गया, जैसाकि प्रयास हो रहा है, तो इतना निश्चित है कि इंका उम्मीदवार तीसरे नम्बर पर रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में कुर्मियों का दबदबा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र से हमेशा शक्तिशाली कुर्मी उम्मीदवार को ही बढ़त मिलती रही है। हरिजन मतदाता न तो कांग्रेस के साथ है और न ही लोकदल-ब के साथ। वह तो आंख बंद करके बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं। इस कारण भी इंका को ही नुकसान पहुंचेगा।

इंका उम्मीदवार को सर्वाधिक परेशानी अपने ही दल के असंतुष्टों के इस प्रचार से हो रही है कि जब पार्टी उम्मीदवार अपने एक गज के फासले पर खड़े व्यक्ति को न तो पहचान सकता है और न उसकी बात सुन सकता है, तो वह जनता की समस्यायें कैसे सुलझायेगा। पार्टी के लोग ही अपने उम्मीदवार की वृद्धावस्था का मजाक उड़ा रहे हैं।

लोकदल-ब के गोपीनाथ वर्मा यह सीट आसानी से जीत लेगें, इस तरह की हवा इस इलाके में बनने लगी है।

छपरौली: क्या गुल खिलेगा?: चौधरी चरणसिंह की पुत्री सरोज वर्मा की मौत से रिक्त हुई छपरौली सीट का चुनाव बहुत कुछ अजीतसिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। यह सीट और क्षेत्र शुरू से ही चौधरी चरणसिंह की जागीर रहा है। आजादी के बाद से लेकर १९७४ तक चौधरी चरणसिंह इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वर्ष १९७७ में, जब वह बागपत संसदीय सीट से लोकसभा में चले गये, तब छपरौली से जनतापार्टी के नरेन्द्रसिंह ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। नरेन्द्रसिंह दुबारा १९८० में भी विजयी हुए, लेकिन १९८५ के चुनाव में चौधरी साहब ने अपनी पुत्री सरोज वर्मा को टिकट देकर जितवा दिया। सरोज को ३३,९२२ तथा तत्कालीन इंका उम्मीदवार सोमदत्त शास्त्री को २६,१७४ वोट मिले थे।

अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। सोमदत्त शास्त्री, इंका छोड़कर जनमोर्चा में आ चुके हैं। चौधरी चरणसिंह से बगावत कर १९८५ में सरोज वर्मा के खिलाफ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाले (प्राप्त मत १०५१६) रामपाल सिंह तोमर को इस बार इंका ने मैदान में उतार दिया है। जनता पार्टी ने पूर्व विधायक नरेन्द्र सिंह को टिकट दिया है।

रामपाल सिंह तोमर को इंका का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा सदस्य शान्ति त्यागी की रही है। रामपाल सिंह को कुछ माह पूर्व वह ही इंका में लाये थे। पिछली १६ मई को जब प्रधानमंत्री मेरठ में रोजा आफ्तार के लिए गये थे, तभी रामपाल सिंह को प्रधानमंत्री से मिलाया गया था। रामपाल सिंह में वे सभी गुण हैं जिनका इस्तेमाल चौधरी चरणसिंह चुनाव जीतने के लिए करते थे। किसानों में उनका खासा दबदबा है। बूथ कैप्चरिंग के दौरान लाठी का जवाब लाठी से देना रामपाल सिंह अच्छी तरह जानते हैं। फिर इस बार तो वह सत्तापक्ष के उम्मीदवार हैं।

विपक्ष ने जिस तरह की
एकता दिखायी है, उससे अब यह लगने
लगा है कि अगर वीरबहादुर
ने कोई करिश्मा न किया, तो ये
दोनों सीटें (छपरौली और टांडा) भी
विपक्ष की ही झोली में जायेंगी।

इस क्षेत्र में महेन्द्र सिंह टिकैत का भी खासा प्रभाव है। उनकी भारतीय किसान यूनियन का झुकाव जनतापार्टी की ही तरफ है। मैदान में खड़े ग्यारह उम्मीदवारों में भाजपा के ओमप्रकाश भी हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। भाजपा, जनतापार्टी को समर्थन दे रही है।

मेरठ की इंका राजनीति में मोहसिना किदवई और शान्ति त्यागी के दो अलग-अलग गुट हैं। यही वजह है कि रामपाल सिंह को टिकट मिलने के बाद मोहसिना गुट के लोग बगावत पर उतारू हैं। यह गुट जिला परिषद सदस्य ब्रजपाल सिंह को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहा था। वह पुराने कांग्रेसी हैं। जिले की राजनीति में ब्रजपाल सिंह हमेशा चौधरी चरणसिंह के विरोधी रहे हैं। ब्रजपाल को टिकट दिलाने के प्रयास खरखौंद (मेरठ) के इंका विधायक राजेन्द्र शर्मा भी कर रहे थे। शर्मा का छपरौली के ब्राह्मणों पर अच्छा असर है। देशखाप के मुखिया तथा महेन्द्र सिंह टिकैत के समधी सुखवीर सिंह के भी ब्रजपाल सिंह से घनिष्ठ संबंध हैं। अब ब्रजपाल सिंह को टिकट न मिलने से देशखाप के लोग भी इंका से नाराज हो गये हैं। छपरौली में इस खाप के ३५ गांव हैं।

एक ओर जहां विपक्षी एकता का लाभ जनता उम्मीदवार नरेन्द्र सिंह को मिल रहा है, वहीं इंका के लोगों की अन्दरूनी घात का शिकार रामपाल सिंह हो रहे हैं। छपरौली में मतदाताओं की संख्या लगभग एक लाख, ६० हजार है, जिसमें करीब ५० प्रतिशत मतदाता जाट हैं। इंका और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार दोनों ही जाट हैं। लेकिन छपरौली के जाटों में आज भी चौधरीचरण सिंह के प्रति वैसी ही श्रद्धा है, जैसी उनके जीवित रहने के समय थी। यही वजह है कि एक गैरजाट से विवाहित होने के बावजूद रुष्ट जाट मतदाताओं ने चौधरी की पुत्री होने के कारण सरोज वर्मा को पिछले चुनाव में जिताया था।

नरेन्द्र सिंह, अजीत सिंह की पसंद के उम्मीदवार हैं। इस कारण अधिकांश जाटों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। इंका की ओर से इस बात की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गयी है कि किसी भी कीमत पर 'बूथ कैप्चरिंग' न होने पाये। इसके लिए रामपाल सिंह ने भी अपने 'आदमी' तैयार कर लिये हैं। हारजीत का निर्णय मात्र पांच हजार मतों के बीच ही होगा, ऐसा हवा का रुख देखने से पता चलता है। आश्चर्य नहीं होगा, अगर यह सीट इस बार फिर विपक्ष के ही हाथ में रहे।

—लखनऊ ब्यूरो

उषा आज! उषा अब!

चमकते दमकते मोतियों से सफ़ेद. स्टैला, पल्सर, प्राइमा.

सुनहरे व भूरे सरताज: कोहिनूर सुपर डीलक्स, सेनेटर और नया सजीला तीन-ब्लेड पल्सर.

उषा के विस्तार का जवाब नहीं. विलासपूर्ण आराम भी, आसान दाम भी. हर पसंद, हर डिज़ाइन के पंखे.

और कई दूसरे आकर्षक सितारे भी–तरह-तरह के टेबिल वॉल कैबिन, पैडेस्टल और वेंटिलेटिंग पंखे. उषा की उत्तम तकनीक से गढ़े, दुनिया के पारखी लोगों के लिये उषा पंखे–रूप उत्तम, बिकें अधिकतम.

कोहिनूर सुपर डीलक्स
पल्सर डेकोरेटिव
कोहिनूर सुपर डीलक्स
पल्सर एक्सपोर्ट
USHA
महलों का 'मोती'
U S H उषा A

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

टी वी की सर्विस होनी चाहिए तब, जब यह काम कर रहा हो पूरी कुशलता से.

इसे हम कहते है प्रीवेंटिव मेन्टेनेन्स यानी खराबी की रोकथाम करने वाली देखभाल. जिसे हम हर पिरामिड टी वी के लिए बिल्कुल मुफ़्त करते हैं.

पहले वर्ष के दौरान, हर तीन महीने में हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा.

वह आपके एन्टीना को ठीक-ठाक करेगा, आपके सेट की सफ़ाई करेगा, और पूरी तरह उसकी जांच-पड़ताल करेगा. यदि कोई छोटी-मोटी खराबी होगी, तो उसी वक़्त ठीक कर देगा.

ये तो हमारी सेवाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

आपका पिरामिड टी वी घर पर पहुंचने के दो हफ़्ते बाद ही कंपनी का इंजीनियर आपके घर पहुंचकर देखेगा कि आपका सेट सही तरीके से लगाया गया है या नहीं? और यह बढ़िया ढंग से काम कर रहा है या नहीं?

और इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो फ़ोन कीजिए, हमारा इंजीनियर २४ घंटे या इससे भी कम वक़्त में आपकी सेवा में मौजूद होगा !

बदकिस्मती से कभी आपका सेट मरम्मत के लिए सर्विस सेन्टर ले जाना पड़े तो बदले में हम आपको दूसरा सेट देंगे. यानी आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम 'चित्रहार' देखने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी !

दरअसल गारंटी है किसकी सुरक्षा : आपकी या निर्माता की?

आज ज्यादातर गारंटियां देखकर आप सोचते होंगे कि आख़िर इसका मतलब क्या है? इनमें लंबी-चौड़ी सूची तो उन नामों की होती है जिनकी गारंटी नहीं दी जाती.

और जिस सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में निर्माता जान-बूझकर ख़ामोश रहते हैः वह है पिक्चर ट्यूब.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड की गारंटी इसके ख़रीदारों को ध्यान में रखकर दी जाती है.

बग़ैर किसी संशय के, पूरी तरह बेनुक्स गारंटी. जिसमें पिक्चर ट्यूब भी शामिल होती है. ऐसी गारंटी जो आपको सुरक्षा देती है... न कि निर्माता को.

वेव सॉल्डरिंग : भारत के १०० से भी अधिक टी वी जो नहीं करते.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए वेव सॉल्डरिंग बिल्कुल वैसी ही ज़रूरी चीज़ है जैसी कि कपड़ों के लिए सिलाई : यानी हर जोड़ पूरे एहतियात और मज़बूती के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए.

बदकिस्मती से भारत के अधिकांश टी वी में आज भी सॉल्डरिंग हाथों से की जाती है. एक ऐसा घटिया तरीका जो टी वी की परिपूर्णता में सबसे बड़ी रुकावट है.

कुछ गिने-चुने ब्राण्डों में केवल पिरामिड ही ऐसा एकमात्र टी वी है जिसमें इस्तेमाल की जाती है वेव सॉल्डरिंग— पूरी तरह अचूक एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया जो दिलाती है सौ-फ़ीसदी बेहतरीन कामगिरी.

बिल्कुल वही फ़र्क, जो मशीन की सिलाई और हाथ से की जानेवाली कच्ची सिलाई के बीच होता है.

अधिकार से इंतज़ार तक : लगातार ४८ घंटे का कड़ा परीक्षण दौर.

हर पिरामिड टी वी को गुजरना होता है लगातार ४८ घंटे चलते रहने की कड़ी अग्नि परीक्षा से.

इस तरह की अग्नि परीक्षा के कुछ अपने फ़ायदे हैं.

सेट में किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी हो तो वह छुप नहीं सकती और उस को तुरंत दुरुस्त किया जा सकता है. इस प्रकार यह पक्का हो जाता है कि पिरामिड का कोई भी दोषपूर्ण सेट बाजार में आ ही नहीं सकता.

ज़्यादातर टी वी इस तरह का परीक्षण तो करते हैं पर सिर्फ़ ६ घंटे तक. कुछ एक १२ घंटे तक. और कुछ २४ घंटे... लेकिन इससे अधिक नहीं.

पिरामिड में एक ख़ासियत नहीं जो ज़्यादातर दूसरे टी वी में होती हैं : धूल-गर्द.

धूल-गर्द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की सबसे ख़तरनाक दुश्मन है.

बदकिस्मती से ज़्यादातर टी वी जब कारखाने से निकलते हैं तो इनमें धूल या गर्द मौजूद होती है.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड कारखाने में तकनीकी साफ़-सफ़ाई के सबसे ऊंचे स्तर को कायम रखा जाता है. तभी तो हर पिरामिड टी वी तैयार होता है पूरे धूल नियंत्रित वातावरण में.

पिरामिड : न कोई चिंता, न कोई ग़म इस टी वी में ऐसा दम.

टी वी ख़रीदते समय आपका पहला सवाल यही होता है— "इसके निर्माता कौन है?"

और हमारे पास है इसका बहुत ही ठोस और विश्वसनीय जवाब. क्योंकि पिरामिड के निर्माण के पीछे है ६०० करोड़ रुपये की बिक्री का— लालभाई ग्रुप.

बरसों की मेहनत और लगन के बलबूते पर लालभाई ग्रुप ने टेक्सटाइल्स, एअरकंडीशन से, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और फ़ायनान्स के क्षेत्र में ऊंचे दर्जे के उत्पादन तैयार करके अपनी खास पहचान बनाई है.

इसीलिए तो जब आप पिरामिड खरीदते हैं तो आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती.

क्योंकि आपकी तमाम फ़िक्रों का बोझ पहले ही उठा लिया है लालभाई ग्रुप ने.

पिरामिड पेश करते हैं पिरामिड २००० ई, पिरामिड २००० आर, पिरामिड प्लस (रिमोट और नॉन रिमोट), पिरामिड परफ़ेक्ट और पिरामिड २०९ जे कलर में. पिरामिड १४२, पिरामिड १४५ टी और पिरामिड १४५ ई, १४" ब्लैक एण्ड व्हाईट पोर्टेबुल में, पिरामिड ५१० और पिरामिड ५११ २०" ब्लैक एण्ड व्हाईट में.

पिरामिड . . . इसमें कोई शक नहीं.

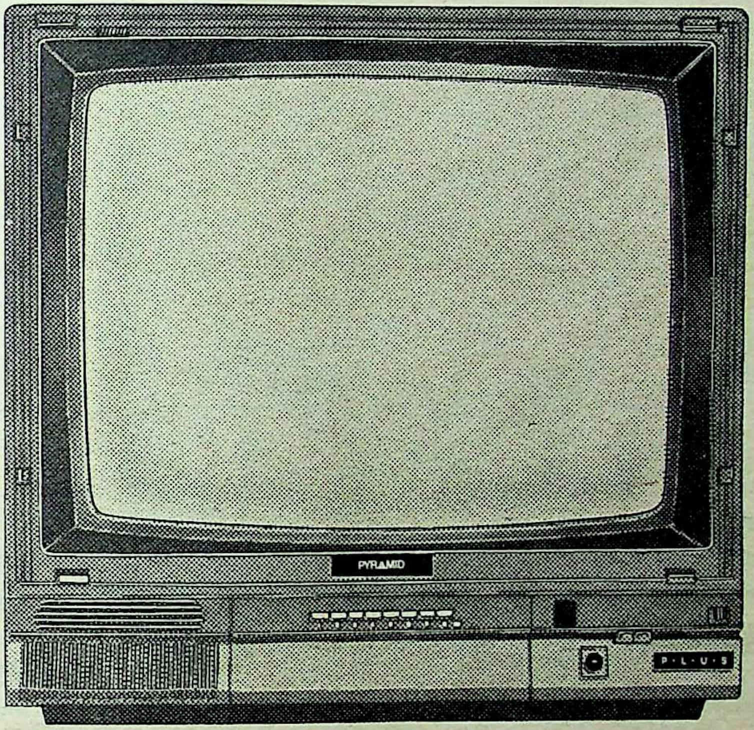

PYRAMID
COLOUR TELEVISION

जापानी टेक्नालॉजी का उत्पादन.

Trikaya.AMED.13.88.HIN

बूटा सिंह

अभी हमें समूचे पंजाब में लड़ाई लड़नी है

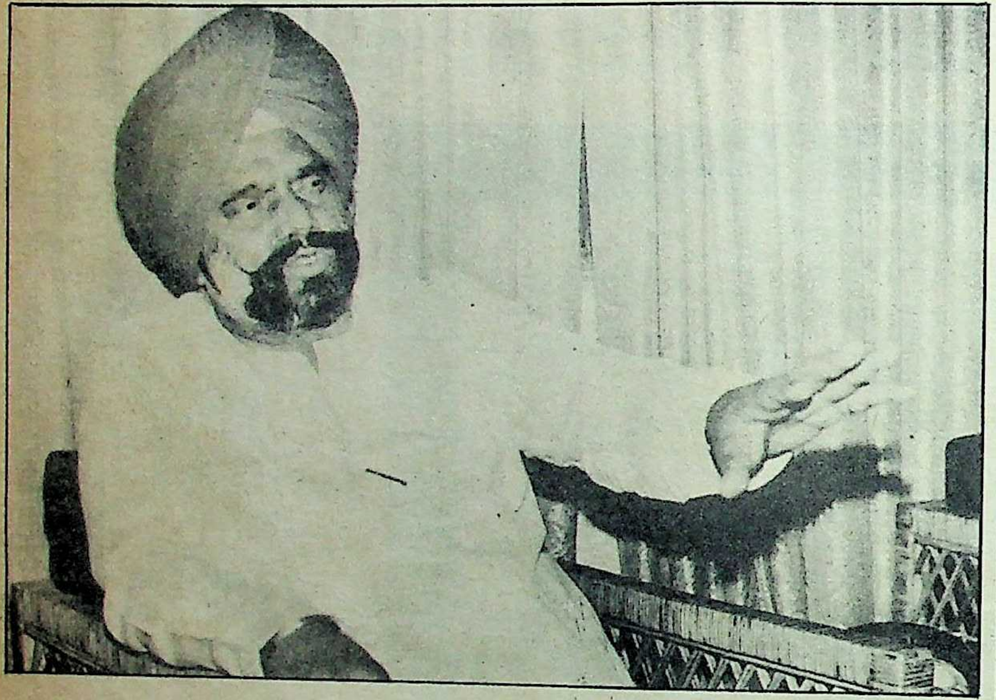

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने सफलता की जितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, उतने ही वह विवादग्रस्त भी हुए हैं। राजीव के सिपहसालार की अपनी भूमिका में जहां विपक्ष शासित राज्यों को सांसत में डालने में उन्हें महारत हासिल है, वहीं इंका शासित मुख्यमंत्रियों के बीच भी दहशत फैलाने में उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। राजनीतिक जनाधार से वंचित बूटा सिंह का मूलाधार गांधी परिवार के प्रति उनकी अटूट स्वामिभक्ति है। इसलिए बूटा सिंह को राजस्थान से जिता कर संसद में लाया गया है। इसी के तहत एक ओर वह प्रधानमंत्री के हर हुक्म की तामील करने वाले सेवक हैं, तो दूसरी ओर उन पर आंच न आने देने वाले 'शाक आबजर्वर'। इस दोहरी भूमिका के तहत उन्हें कोई भी काम करने का हथकंडा अपनाने में न देर लगती है, न हिचक होती है। इसी कारण उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। आलोचकों में विपक्ष भी शामिल है और खुद उनकी पार्टी के लोग भी।

गांधी परिवार में विश्वसनीयता जमाने में सेवाभाव के अतिरिक्त सही समय पर सही स्थान पर उनकी मौजूदगी का भी प्रचुर हाथ है। 'एशियाड' के समय इन्होंने खेलमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं पेश कीं, तो 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' के समय निर्माणमंत्री के रूप में। अकालतखत के निर्माण के समय उन्होंने जो सेवा की, उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक ओर सिख पंथ ने उन्हें तनखैया घोषित कर दिया, तो दूसरी ओर पंजाब में वह सबकी नफरत मोल ले बैठे। पंजाब समस्या सुलझाने में अपने अनथक प्रयासों के बावजूद वह आरोपों के दायरे से बाहर नहीं हैं। इसमें मिली सफलता-असफलता कदाचित उनके राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव का मानक सिद्ध होगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने 'आपरेशन ब्लैक थंडर' की अभूतपूर्व सफलता के तुरंत बाद ही पंजाब समस्या पर 'माया' से जो विस्तृत बातचीत की, उसके अंश:

माया: स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के बाद भी पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी आतंकवादी हत्याओं का मूल कारण क्या है?

बूटा सिंह: यह जानने के पूर्व अकाली आंदोलन पर नजर डालना जरूरी है। दरअसल आतंकवादी शुरू से ही—जब से १९८१ से नया अकाली आंदोलन शुरू हुआ— आहिस्ता-आहिस्ता उसमें घुस गये। अकाली नेतृत्व को इसका पता ही नहीं था कि ये बहुत गलत लोग हैं। इसलिए इस आंदोलन में उनके प्रवेश पर अकालियों ने कोई रुकावट नहीं डाली। आपको याद होगा कि पंजाब में आतंकवाद की जड़ नक्सलवाद से प्रारंभ हुई। प्रकाश सिंह बादल उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया। मगर बहुत से नक्सलवादियों ने तत्कालीन सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) से समझौता कर लिया। नतीजतन बहुत से नक्सलवादी एसजीपीसी में प्रवेश कर गये। वे बड़े योजनाबद्ध ढंग से गुरुद्वारों में ग्रंथियों, सेवादारों और कर्मचारियों के रूप में तैनात हो गये और अपने मन्तव्यों को पूरा करने के लिए काम करने लगे। उस समय नक्सलवादी आंदोलन का केन्द्र दुर्भाग्यवश मेरा अपना ही क्षेत्र था। यहां सरहिंद, रोपड़, होशियारपुर जिला, सतलज के किनारे के जंगलों आदि में उन्होंने घुसकर अपना गढ़ बना लिया। इन स्थानों पर हथियार इस्तेमाल करने में उनको बड़ी सुविधा थी। इस क्षेत्र में उनका एक अंडरग्राउंड प्रेस भी पकड़ा गया। जब नक्सलवादियों की बढ़ती गतिविधियों को सख्ती से कुचला गया, तो वे एसजीपीसी में प्रवेश कर गये। इसमें गुरुचरण सिंह तोहड़ा ने योजनाबद्ध तरीके से उनकी मदद की। तभी आतंकवाद की जड़ अकाली राजनीति और एसजीपीसी के संगठन में प्रवेश कर गयी।

१९८१ में जब जगदेव सिंह तलवंडी अकाली पार्टी के अध्यक्ष थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलायी और पहली बार एक पार्टी अध्यक्ष (तलवंडी) ने अपनी ही सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन पेश किया, जिसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगाये गये थे। उस समय अकालतखत के जत्थेदार ने बीच-बचाव कराया। किंतु नतीजा यह हुआ कि बादल की सरकार टूट गयी। उसी समय पानी और आर्थिक मसले को लेकर अकाली दल ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जो बाद में विफल हो गया। बाद में उन्होंने धर्म को अपने आंदोलन से जोड़ दिया। इसी की आड़ में नक्सलवादियों ने उसके भीतर घुसपैठ की। इसी आंदोलन के समकक्ष निरंकारियों से हुई मुठभेड़ में जरनैल सिंह भिंडरांवाले का हिंसक गुट उभरकर सामने आया। अकालियों ने अपनी घटती ताकत को देखकर भिंडरांवाले को अपने साथ शामिल कर लिया। भिंडरांवाले ने धर्मयुद्ध का नारा दिया। इस प्रकार आर्थिक मांगों को लेकर शुरू हुआ अकाली आंदोलन अंततः आतंकवाद के उदय का कारण बना। इसका उभार इतना जबर्दस्त हुआ कि

तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार इस पर काबू पाने में विफल रही। अंततः 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' के तहत सैन्य बल का सहारा लेना पड़ा।

माया : ***इस बार स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों की सफाई के लिए आपरेशन ब्लैक थंडर में अपेक्षाकृत कम शक्ति प्रयोग के बाद मिली सफलता का मुख्य कारण क्या है?***

बूटा सिंह : इसके दो मुख्य कारण हैं। 'आपरेशन ब्लू स्टार' के समय जिस ढंग से अंदर हथियार जमा हुए थे और पूरे देश के तथा पंजाब के लोगों को उत्प्रेरित किया गया था कि हमारा धर्म खतरे में है, लोग धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो जायें, क्योंकि हरमंदिर साहिब को बचाना है, उसका इस बार अभाव था। इस बार प्रचार ठीक उसके विपरीत हुआ था। लोगों को दो-तीन महीने पहले ही पता चल गया था कि हरमंदिर साहिब के अंदर कुछ आतंकवादी जुड़ गये हैं और वहां उन्होंने खालिस्तान का कार्यालय तक बना लिया है। पहले खालिस्तान का कहीं कोई नारा या नाम नहीं था। खालिस्तान के साथ सिखों का बहुमत नहीं है। खालिस्तान से उनको एक प्रकार से नफरत है। पहले हरमंदिर साहिब के नाम पर एकजुट किया गया था। इस बार कोशिश खालिस्तान के नाम पर की गयी थी। किंतु खालिस्तान के नाम पर लोग जमा होने को तैयार न हुए। फलस्वरूप अंदर बहुत कम लोग गये। जो साधारण लोग भीतर मौजूद थे और जिनकी तादाद लगभग ७५० थी, उनसे जब हमारे अर्द्धसैनिक बल के लोगों ने अपील की, तो वह पहले ही दिन बाहर आ गये। अंदर केवल कट्टरपंथी रह गये थे। इनसे निपटना हमारे लिए आसान था। स्वर्ण मंदिर के भीतर उससे लगी इमारतों पर आतंकवादियों ने अपने मोर्चे बना रखे थे। उसे नकारा करने के लिए अर्द्धसैनिक बल ने अपने मोर्चे बनाये थे, जिनके द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। इस सफलता के दो मुख्य कारण हैं। एक तो लोगों को खालिस्तान के नाम से नफरत है। दूसरा लोगों को मालूम था कि हरमंदिर साहिब के अंदर वे (आतंकवादी) खुद हैं जो हरमंदिर साहिब का असम्मान कर रहे हैं। साथ ही यह भी कि अर्द्धसैनिक बल जो कुछ भी कर रहे थे वह सिखों के हित में था।

माया : ***स्वर्ण मंदिर के भीतर तो सरकार को सफलता मिल गयी है। किंतु उसके बाहर आतंकवादियों ने कुछ ज्यादा ही हिंसक कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। क्या वह ऐसा कुंठा, निराशा में कर रहे हैं या आपकी जीत को निष्प्रभावी करना चाहते हैं?***

बूटा सिंह : हिंसक गतिविधियों में उभार गत नवंबर से आया है। इस दौरान हथियार न सिर्फ ज्यादा आये हैं, बल्कि बहुत खतरनाक किस्म के आये हैं। पहले आतंकवादी अधिकांशतः पिस्तौल या स्टेनगन का इस्तेमाल करते थे। आजकल इन हथियारों का कोई नाम भी नहीं लेता, क्योंकि आतंकवादियों के पास ऐसे गंभीर हथियार हैं जो आम सैनिकों के पास भी नहीं हैं और जिनकी संहारक्षमता अत्यधिक है। ये एक बार मे दस-बारह लोगों को आसानी से मार सकते हैं। इसी तरह राकेट प्रक्षेपास्त्र भी बड़ी भारी तादाद में आतंकवादियों के हाथ आ गये हैं। इस प्रकार उनका अपना संगठन ही नहीं मजबूत हुआ, मारने की क्षमता भी बढ़ गयी है। इससे हत्याओं में इजाफा हुआ है। गांवों में की जाने वाली हत्याएं उनकी कुंठा की ही निशानी हैं। हरमंदिर साहिब में उन्हें जो मुंह की खानी पड़ी है, उसकी वह भरपाई करना चाहते हैं।

माया : ***कहा जाता है कि मात्र १० प्रतिशत आतंकवादी हरमंदिर साहिब के अंदर थे। शेष बाहर हैं जो बढ़ती आतंकवादी कार्रवाइयों में संलग्न हैं। सरकार इनके नियंत्रण की दिशा में क्या कदम उठा रही है?***

बूटा सिंह : ऐसा कोई प्रतिशत निकालना तो मुश्किल है, क्योंकि इनकी गिनती संभव नहीं। यह सही है कि अंदर जितने आतंकवादी थे, उनके सरगना आज बाहर हैं। भीतर पाये जाने वालों में एक-दो अवश्य शीर्षस्थ नेता थे, किंतु वे विशेषकर खालिस्तान के प्रचार कार्य में जुटे थे। अन्य चोटी के नेता बाहर हैं— कुछ देश में और कुछ पाकिस्तान में। हमें भली-भांति मालूम है कि यह लड़ाई लंबी है। अभी हमने जो सफलता पायी है, वह सीमित है। अभी हमें समूचे पंजाब में लड़ाई लड़नी है और आतंकवाद से निजात पानी है।

माया : ***क्या स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों का मुख्यालय था?***

बूटा सिंह : यह कहना मुश्किल है कि इका मुख्यालय कहां है, क्योंकि इनके छोटे-छोटे संगठन हैं, जिनके अलग-अलग मुख्यालय हैं और उनमें वे छिपे रहते हैं। स्वर्ण मंदिर को इन्होंने अपना चिह्न इसलिए बनाया था कि स्वर्ण मंदिर की अपील समूचे देश-और विदेशों के सिखों के बीच जाती है। इसे हमने अवश्य चकनाचूर किया है। वैसे इन आतंकवादियों के दफ्तर व मुख्यालय बड़े अंडरग्राउंड किस्म के हैं। 'केएलएफ' का अलग है, 'केसीएफ' का अलग है, तो वह भिडरांवाले 'टाइगर फोर्स' का अलग है और पंथक कमेटी का अलग है। यह जरूर है कि जो इनके हथियार स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे हुए थे, उनका पूरी तरह सफाया कर दिया गया है।

यह सही है कि अंदर जितने आतंकवादी थे, उनके सरगना आज बाहर हैं। भीतर पाये जाने वालों में एक-दो अवश्य शीर्षस्थ नेता थे, किंतु वे विशेषकर खालिस्तान के प्रचार कार्य में जुटे थे। अन्य चोटी के नेता बाहर हैं—कुछ देश में और कुछ पाकिस्तान में।

माया : ***अब ऐसी स्थिति में आज उनको दिशानिर्देश कहां से मिल रहा है और कौन दे रहा है?***

बूटा सिंह : अभी तो ज्यादातर कार्रवाई पंजाब के भीतर से ही हो रही है। वैसे भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान के भीतर २०-२५ किलोमीटर की सीमा तक इनके अपने अड्डे हैं, जहां ये छिपते हैं और जहां से ये कार्रवाइयां करते हैं। वहीं से वे अपने प्रचार-प्रसार की मुहिम भी चलाते हैं।

माया : ***सीमा पर बाड़ लगाने के बाद से हथियारों की सप्लाई रोकने में कितनी मदद मिली है?***

बूटा सिंह : अभी हमने जम्मू से लेकर गंगानगर (राजस्थान) तक जो योजना लागू की है, उसमें एक तिहाई क्षेत्र में हम बाड़ लगायेंगे और दो तिहाई क्षेत्र में अधिक प्रभावकारी चौकसी करेंगे। इसके तहत एक ओर पुलिस गश्त बढ़ाने का काम करेंगे और दूसरी ओर चौकसी चौकियों की दूरी कम करेंगे, जिससे दोनों में आपसी तालमेल से पूरी चौकसी रहे।

माया : ***अब तक जितना काम हुआ है, उससे क्या भावी सफलता की आशा बंधी है?***

बूटा सिंह : हां, अवश्य।

माया : ***पंजाब बहस के दौरान आपने संसद के पिछले सत्र में जिस तीन सूत्री रणनीति की घोषणा की थी, उसमें कितनी कामयाबी मिली है?***

बूटा सिंह : असली कामयाबी तो मैं तब मानूंगा, जब हम इन देश विरोधी ताकतों को जड़ से खतम कर देंगे। लेकिन यह जरूर है कि अब तक की उपलब्धियों से हमें विश्वास हो गया है कि हम कामयाबी की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।

माया : ***स्वर्ण मंदिर के भीतर वर्तमान स्थिति क्या है?***

बूटा सिंह : लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हरमंदिर साहिब के दरवाजे दर्शनार्थियों के लिए पुनः खुल गये हैं। लोग खुलकर और निडर होकर दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन में शामिल होते हैं।

माया : ***स्वर्ण मंदिर के संबंध में सरकार की भावी रणनीति क्या होगी, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह पुनः आतंकवादियों का शरणस्थल न बन जाये?***

बूटा सिंह : सरकार ने स्वर्ण मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तय किया है कि एसजीपीसी या कोई अन्य संस्था जो भी स्वर्ण मंदिर की जिम्मेदारी लेने आये, उसके साथ कुछ बुनियादी मुद्दे तय कर लिये जायें, जिससे अवांछित लोग न तो भीतर प्रवेश पा सकें, न अपने अड्डे बना सकें और न यहां से देश विरोधी प्रचार कर सकें। दूसरे, स्वर्ण मंदिर परिसर के अधिकांश भाग बहुत पुराने समय से चले आ रहे थे, जिनमें आम जनता जाती थी, पार्क थे, सड़कें थीं,

एसजीपीसी के दफ्तर और सराय आदि थीं। इनको न तो हम हरमंदिर साहिब का हिस्सा मानते थे और न वे लोग मानते थे। लेकिन आतंकवादियों के डर से उन्होंने इन सब क्षेत्रों को भी हरमंदिर साहिब का भाग घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि इतनी किलाबंदी हो गयी है कि कोई देख ही नहीं सकता कि भीतर क्या हो रहा है? इसलिए इस भाग को अलग करना पड़ेगा और जो परिक्रमा के अंदर किलाबंदी बना दी है, कमरे बना दिये हैं, एसजीपीसी ने स्वयं माना है कि वे कमरे गिराने पड़ेंगे। वरना इन लोगों की घुसपैठ भीतर कम नहीं होगी। हमारा प्रयास ऐसे हालात पैदा करने का होगा, जिससे हरमंदिर साहिब की पवित्रता बनी रहे। उसके बाद ही हम इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे।

माया : ***पंजाब प्रशासन कितना सक्षम है? उस पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार, नौकरशाही की अक्षमता और लालफीताशाही के आरोपों में कितनी सचाई है?***

बूटा सिंह : ये तीनों आरोप किसी भी सरकार पर लगाये जा सकते हैं। किंतु पंजाब प्रशासन पर कोई भी फैसला देने से पहले हमें इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिए कि वह किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। चाहे वह पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग अथवा जिला अध्यक्ष हों। इन सबको अपने पर ही नहीं, अपने परिवार पर भी हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किसी कर्मचारी ने हिम्मत बटोर कर काम किया है, तो उसके समूचे परिवार को खतम कर दिया गया है। इन कठिन हालात में भी शासन आगे बढ़कर काम कर रहा है जो काफी प्रभावी है। आज राज्य के कुछ सीमित क्षेत्र में ही आतंकवाद का प्रभाव है। गुरदासपुर की दो तहसीलें, अमृतसर की दो तीन तहसीलें और फरीदकोट का कुछ भाग है, जहां ये अपनी थोड़ी बहुत कार्रवाइयां कर रहे हैं। शेष राज्य में प्रशासन प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। इसका बड़ा सबूत यह है कि पंजाब मुख्य रूप से कृषि प्रदेश है। देश भर में भयंकर सूखे के कारण उत्पादन कम हुआ। किंतु पंजाब में सूखे के बावजूद कृषि उत्पादन कम नहीं हुआ है। रही रिश्वतखोरी की बात, तो जब भी ऐसी किसी वारदात का पता चलता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन पूरा राजनीतिक सहयोग न मिल पाने के बावजूद जनता के बीच जाता है। एक बहुत अच्छी बात है कि राज्यपाल ने लोकशक्ति के जरिए काम करने का बीड़ा उठाया है। वह गांवों, तालुकों, जिलों में जा-जाकर लोगों की समस्याएं वहां के बीडीओ, डिप्टी कमिश्नर आदि के सम्मुख सुनते हैं और जहां तक संभव होता है, तत्काल समाधान करते हैं। मेरी समझ में बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर शासन सुचारु और संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

माया : ***जहां तक प्रशासनिक अक्षमता का प्रश्न है, कहा जाता है कि इसके लिए काफी हद तक केंद्र जिम्मेदार है। क्योंकि उसका निरंतर हस्तक्षेप बना रहता है, जिसके तहत प्रशासन के हाथ कभी बांध दिये जाते हैं, तो कभी खोल दिये जाते हैं!***

बूटा सिंह : जहां तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, उसमें केंद्र की ओर से निश्चित ही लगातार निगरानी होती है। जहां तक राज्य के नित्यप्रति के कामकाज का सवाल है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं, जिसमें केंद्र ने दखल दिया हो। आतंकवाद-अलगाववाद के खिलाफ राज्य में जो अभियान चल रहे हैं, उनमें हम हमेशा चौकसी करते रहते हैं, जिससे उन्हें भी लाभ होता है और हमें भी। हमें यह भी पता चलता है कि कहां क्या हो रहा है और कहां क्या कमी है, कहां हमें सख्ती करनी पड़ेगी और क्या-क्या कदम उठाने पड़ेंगे। राज्य को भी अच्छे यंत्र मिलते हैं, अच्छा परामर्श और समुचित सहायता मिलती है। किसी प्रकार के राजनीतिक दखल का उदाहरण तो अभी तक मेरे सामने नहीं आया है।

माया : ***गत दिसंबर-जनवरी में जब सहसा हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई, तो उसका मूल कारण यह समझा गया कि सुशील मुनि के द्वारा आतंकवादियों से जो वार्ता चल रही थी, उस बीच प्रशासन से नरमी का रुख अपनाने को कहा गया था!***

> जहां तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, उसमें केंद्र की ओर से निश्चित ही लगातार निगरानी होती है। जहां तक राज्य के नित्यप्रति के कामकाज का सवाल है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं, जिसमें केंद्र ने दखल दिया हो। आतंकवाद-अलगाववाद के खिलाफ राज्य में जो अभियान चल रहे हैं, उनमें हम हमेशा चौकसी करते रहते हैं, जिससे उन्हें भी लाभ होता है और हमें भी।

बूटा सिंह : इसमें राई-रत्ती सचाई नहीं। किसी ने नरमी का रुख अपनाने का आदेश नहीं दिया था। बल्कि हमने तो बार-बार राज्यपाल और रिबेरो कहा था कि हमारी ओर से कोई नरमी बरतने का आदेश नहीं है। उलटे हम तो बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ? जब प्रकाश सिंह बादल और उनके साथी बाहर आये, तो आम लोगों में धारणा बनी कि अब बादल सरकार बनायेंगे। पंजाब प्रशासन में कुछ ऐसे तत्व थे, जिन्होंने यह सोचकर कि अब शायद बादल की सरकार बन जायेगी, अपना रवैया थोड़ा ढीला कर दिया। जैसे कहा जाता है, घोड़ी हमेशा अपने सवार को पहचानती है।

माया : ***बात मनोबल क्षीण होने की भी है, जिसमें बदलती नीतियों का बड़ा हाथ रहा है। जैसे जब जसबीर सिंह रोड़े को, जिनकी गिरफ्तारी के इतने प्रयास किये गये थे, छोड़ दिया गया, तो प्रशासनिक मनोबल कम हो गया था। कारण, अधिकारियों को लगा होगा कि आज रोड़े को छोड़ दिया गया है, तो कल वह सत्तासीन भी हो सकते हैं।***

बूटा सिंह : जब इन ग्रंथियों को छोड़ा गया, तब उन्हें यह स्पष्ट रूप से जता दिया गया था कि इस कार्रवाई (ग्रंथियों की रिहाई) और आतंकवादियों के खिलाफ हमारी चल रही लड़ाई में कोई संबंध नहीं है। हमारा यह प्रयास रहा है कि धार्मिक पहलू को आतंकवाद से दूर किया जाये। क्योंकि ये लोग अकसर हरमंदिर साहिब का नाम इस्तेमाल करते हैं, पंथ का नाम इस्तेमाल करते हैं, अकाल तखत का नाम इस्तेमाल करते हैं। किंतु ये (ग्रंथी) लोग जब यह कहकर आगे आये कि आतंकवादी हमारे धार्मिक विश्वासों का लाभ उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनको भी मौका दें। मगर इसका आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में कोई दखल नहीं है।

माया : ***इस समय जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्या वह इस बात का द्योतक है कि अब नरम विकल्प नहीं रह गये हैं या कम हो गये हैं?***

बूटा सिंह : देखिए विकल्प तो प्रधानमंत्रीजी ने हमेशा दोनों ही खुले रखे हैं। इसमें कभी कोई संदेह नहीं आने दिया गया है। जहां केवल सख्ती से ही निपटा जा सकता है, वहां पर सख्ती ही बरती गयी है। जहां नरम रवैये से काम बन सकता है, वहां नरम रवैया ही अपनाया जायेगा। जो भी संगठन अथवा कोई दल देश के संविधान में विश्वास रखता हुआ, देश की एकता-अखंडता को मानता हुआ और हिंसात्मक कार्रवाइयों को छोड़कर हमसे बात करना चाहे, किसी भी मुद्दे पर, तो हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, हमारा रवैया नरम रहेगा। जहां तक निर्मम हत्याओं का, कत्ल और गारत का और पंजाब में खालिस्तान की मांग और प्रचार का सवाल है, उसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जायेगी। इसको कुचलने

के लिए कड़ा-से-कड़ा कदम उठाया जायेगा। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है।

माया: ***भावी कार्रवाई के बारे में क्या आपने कोई सुनिश्चित योजना बनायी है?***

बूटा सिंह: जैसा आपने देखा होगा राज्यपाल ने कहा है कि अब हमारी कार्रवाई का दूसरा चरण लागू हो गया है। इसमें हमें यह देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हत्याएं हो रही हैं, उन पर किस तरह काबू किया जाये। जिन क्षेत्रों में इनके जो छिपने के स्थल हैं, उनको पता लगा कर खतम किया जाये। हम कोशिश करेंगे कि एक-एक नगर को सुरक्षा दस्ता दें, जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो जाये कि उनके जान-माल को खतरा नहीं है।

माया: ***वर्तमान परिदृश्य में आप समस्या का समाधान किस रूप में देखते हैं?***

बूटा सिंह: खालिस्तान की मांग करने वाले तत्वों से, जो हमारे देश की एकता-अखण्डता को नष्ट करने पर तुले हैं, किसी प्रकार के समझौते का सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री ने समझौते के लिए जो परिधि प्रस्तुत की है, उसके अंतर्गत हम हर किसी से बातचीत करने को तैयार हैं।

माया: ***पंजाब में आम धारण है कि पंजाब समझौते का पालन न करने का कारण केंद्र रहा है?***

बूटा सिंह: केंद्र की भूमिका तो इसमें बहुत कम थी। समझौते में ९-१० धाराएं हैं और हर धारा में पूर्वनिर्धारित विस्तृत व्याख्या है कि उस पर कैसे अमल किया जाये। मसलन चंडीगढ़ का मुद्दा लीजिए। यह तय हुआ था कि इस मुद्दे पर एक न्यायिक आयोग बैठेगा जो यह निश्चित करेगा कि उसके बदले में कौन-सा और कितना इलाका हरियाणा को दिया जायेगा। दोनों पक्षों ने अपना केस उसके सामने रखा और जब उसका फैसला आया, उस पर अमल करने की बात आयी, तो हरियाणा ने तो उसे मान लिया, किंतु पंजाब ने पहले नहीं माना। बाद में उसने विधानसभा में तो मान लिया, किंतु कैबिनट की बैठक में उसे नामंजूर कर दिया। ऐसी स्थिति में केंद्र का क्या दोष है? इसी तरह, अधिकांश मुद्दों पर रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। इस सारे मामले में हमारी भूमिका तो एक 'रेफ़्री' की थी। समझौते को अमल में लाने की भूमिका तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की थी। तीनों सरकारों को कैसी भूमिका निभानी थी, उस समझौते में इसकी भी व्यवस्था है। किंतु इसके बावजूद यदि उस पर अमल न हो, तो केंद्र को दोषी ठहराना उचित नहीं।

माया : आरोप है कि पंजाब समस्या के समाधान में वास्तविक बाधा निहित स्वार्थों की है, जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। कारण, अगले चुनावों में वह इसे तुरुप की तरह इस्तेमाल करना चाहती है।

बूटा सिंह : इससे गलत प्रचार और कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की साफदिली का सबूत यही है कि जैसे ही राजीवजी व लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ। उसके तुरंत बाद तमाम दलों के विरोध के बावजूद उसनें बड़ी हिम्मत से चुनाव कराये। हम सिद्ध करना चाहते थे कि हमारा लोकतंत्र में इतना विश्वास है कि बरसती गोलियों में भी हम चुनाव करा सकते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त हुई। यदि इसमें हमारा राजनीतिक स्वार्थ होता, तो क्या हम कभी इतनी भारी भूल करते कि जिसमें हमारी पार्टी ही हार जाती है? हम तो देश के हित को सर्वोपरि मानते हैं।

> हमें अपने देशवासियों, खासकर पंजाब के देशभक्त लोगों पर पूरा विश्वास है। जिस तरह का काम आतंकवादी कर रहे हैं, उसे सिख धर्म में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मासूम लोगों की हत्या करने, बच्चों, महिलाओं को मारने आदि की अनुमति सिख धर्म कदापि नहीं देता। देश के टुकड़े करना भी सिख धर्म के खिलाफ है। अपने अर्ध सैनिक बल पर भी हमें पूरा विश्वास है।

माया : ***जब पंजाब में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के हमारे पास प्रचुर प्रमाण हैं, तो हम उसके विरुद्ध कड़ा रवैया क्यों नहीं अपनाते? या कोई चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं?***

बूटा सिंह : हमारे पास जितने सबूत थे, उन सबको हमने गत १६ मई की बैठक में पाकिस्तान के सामने रख दिया था। किंतु यदि किसी ने तय कर लिया हो कि भारी से भारी सबूत भी हम मानेंगे ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? रही उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात, तो इन हालात में [illegible] से सख्त कदम क्या हो सकता है? अब तो जो हमारे हाथ में आयेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा कि हमने पाकिस्तानी रेंजर्स को भी मार दिया जो कि घुसपैठियों के साथ हमारी सीमा में आ रहे थे। वर्तमान हालत में आप जानते हैं, सख्त कदम क्या हैं? (युद्ध!) किंतु हम चाहते हैं, जहां तक संभव हो, अपने पड़ोसी देश के साथ मामलों को राजनयिक तरीके से और शांति से निपटायें। यद्यपि वह हमारे आंतरिक मामलों में लगातार दखल दे रहा है और अस्थिरता पैदा कर रहा है, किंतु हम चाहते हैं कि राजनयिक तरीकों से उस पर दबाव डालें कि वह हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दे।

माया : ***भविष्य के प्रति आप कितने आशावान हैं? अगला कदम किस ओर होगा?***

बूटा सिंह : हमें अपने देशवासियों, खासकर पंजाब के देशभक्त लोगों पर पूरा विश्वास है। जिस तरह का काम आतंकवादी कर रहे हैं, उसे सिख धर्म में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मासूम लोगों की हत्या करने, बच्चों, महिलाओं को मारने आदि की अनुमति सिख धर्म कदापि नहीं देता। देश के टुकड़े करना भी सिख धर्म के खिलाफ है। अपने अर्ध सैनिक बल पर भी हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मुहिम में उसे कामयाबी मिलेगी।

माया : ***आपकी योजना में मनोवैज्ञानिक पहलू को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? मसलन दिल्ली में ८४ के दंगों के लिए किसी को भी कठघरे में न खड़ा करने से पंजाब का जनमानस उद्वेलित है। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?***

बूटा सिंह : यह कहना सही नहीं है कि मनोवैज्ञानिक पहलू पर सरकार क़ोई कदम नहीं उठा रही है। दिल्ली के दंगों की जांच करने वाले रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार उत्पीड़ित परिवारों के लिए कई समितियां, जैसे पुनर्वास, सहायता समितियां आदि गठित की गयी हैं। आयोग ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार फिलहाल सरकार के हाथ बंध गये हैं।

माया : ***यह बात जोधपुर के नजरबंदों के मसले पर भी लागू है। क्या सरकार इस पर कोई जल्द फैसला लेगी?***

बूटा सिंह : हम उन्हें नज़रबंद नहीं विचाराधीन कैदी मानते हैं। जैसाकि सर्वविदित है, इनकी संख्या ३६६ है। इनमें ४० लोगों, जिनके खिलाफ सामान्य किस्म के मामले थे, की हाल में रिहाई हो गयी है और ५ भागे हुए हैं। इन सभी के खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई चल रही है।

माया : ***गत चार वर्षों में भी आप किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों?***

बूटा सिंह : कानूनी कार्रवाई में देर लगती है। मामले पर कानूनी कार्रवाई जारी होने के कारण, सरकार के सामने और चारा ही क्या है?

—रंजना कक्कड़ और त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव

आपरेशन ब्लैक-थंडर और उसके बाद

सत्यपाल डांग

गत ९ मई को शुरू हुए आपरेशन थंडरबोल्ट-२ ने स्वर्ण मंदिर को आतंकवादी हत्यारों से मुक्त कराने के अपने उद्देश्य में दस दिनों के बाद सफलता प्राप्त की। एक अर्थ में यह एक यादगार अभियान था, जिसे बड़ी कुशलता, दक्षता तथा साथ ही सिखों की धार्मिक भावनाओं और मानवीय प्राण रक्षा के प्रति चिंता के साथ पूरा किया गया। उस अवसर पर फंसे लगभग ८०० भक्तों को भी सफलतापूर्वक निकाला गया, जिनमें स्त्रियां-बच्चे शामिल थे। मारे गये निर्दोषों की संख्या एक या दो ही होगी। आतंकवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए हर संभव मौका दिया गया तथा स्पष्ट था कि भागने का अर्थ होगा गोलियों का निशाना बनना। केवल २० से कुछ ज्यादा लोग मारे गये, जबकि १०० से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों के कर्मियों से केवल एक को ही चोट (संघातक नहीं) आयी। इसके अलावा केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) के डीआईजी एसएस विर्क ९ मई को गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसी वारदात ने अभियान के लिए प्रेरित किया। स्वर्ण मंदिर के पवित्र भाग पर किसी तरह का हमला नहीं किया गया। इस अभियान से कई प्रचलित धारणाएं गलत साबित हुईं तथा इससे लोगों को समूचे संदर्भ को अधिक सही नजरिये से देखने में मदद मिलेगी।

काफी लोगों की तेजी से यह धारणा बनती जा रही थी कि आतंकवादी ऐसे भटके हुए नौजवान हैं जो प्रतिबद्ध हैं। उन्हें कट्टरपंथियों ने सिख धर्म की शिक्षाओं की गलत व्याख्या करके पथभ्रष्ट कर दिया है। निस्संदेह इस कारण तथा हथियार, भरपूर धन और खालिस्तान बनने पर सुनहरे भविष्य के मोह ने सिख युवकों के एक समूह को भटकाने में अहम भूमिका निभायी है। स्वर्ण मंदिर की हाल की घटनाओं ने बहरहाल इस विचार की सचाई पर मुहर लगायी है कि आतंकवादी हत्यारे शुरू से ही असामाजिक तत्व थे। दूसरे लोग खालिस्तान के तर्क के फलस्वरूप इन असामाजिक तत्वों के बीच आ गये थे। इनमें से अनेक तो पेशेवर हत्यारे तक बन गये। हमारा यह मत दो तथ्यों की रोशनी में सही साबित हुआ।

यह एक सचाई है कि ३० सें अधिक आतंकवादियों ने ऐन स्वर्ण मंदिर (परमपावन मंदिर गर्भ) में शरण ली थी, जिसे उन्होंने दो-तीन दिनों तक दूषित किया-मसलन पहली मंजिल के ऊपर के दो कमरों में मल-मूत्र त्याग करके (भले ही बर्तनों का इस्तेमाल किया हो) मंदिर को अपवित्र किया। इससे उजागर है कि किस तरह के ये श्रद्धालु सिख हैं। अंततः इनमें से केवल एक या दो ने जहर खाकर मौत को गले लगाने और शहीद होने की हिम्मत की। बाकी ने सिर झुकाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

आम सिखों ने ग्रंथियों तथा प्रकाश सिंह बादल के स्वर्ण मंदिर पर 'सुरक्षा बलों के कब्जे' के खिलाफ आयोजित मार्च को ठुकरा करके यह सिद्ध कर दिया है कि आतंकवादियों को बहुसंख्यक सिखों का समर्थन मिलने की बात तो दरकिनार, अपने मजबूत गढ़ अमृतसर जिले में प्राप्त जन-समर्थन भी वे तेजी से खोते जा रहे हैं। यह स्वयं सिखों की बड़ी तादाद में हत्याओं, अनेक सिख परिवारों के सफाये और व्यापक रूप से धन ऐंठने एवं किसी को भी न बख्शने—उनको भी नहीं जिन्होंने एक समय उनकी मदद की थी—का नतीजा था।

लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के सदस्य और वयोवृद्ध नेता होने के साथ पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जारी दुर्धर्ष संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में हैं।

CC-0. In Public Do[redacted] Collection, Haridwar

काफी लोगों की तेजी से यह धारणा बनती जा रही थी कि आतंकवादी ऐसे भटके हुए नौजवान हैं जो प्रतिबद्ध हैं। उन्हें कट्टरपंथियों ने सिख धर्म की शिक्षाओं की गलत व्याख्या करके पथभ्रष्ट कर दिया है। निस्संदेह इस कारण तथा हथियार, भरपूर धन और खालिस्तान बनने पर सुनहरे भविष्य के मोह ने सिख युवकों के एक समूह को भटकने में अहम भूमिका निभायी है। स्वर्ण मंदिर की हाल की घटनाओं ने बहरहाल इस विचार की सचाई पर मुहर लगायी है कि आतंकवादी हत्यारे शुरू से ही असामाजिक तत्व थे।

इस अभियान ने भारत सरकार की १९८७ के बाद से सोची-समझी जोखिम उठाने की नीति की व्यापक आलोचना को भी सही साबित किया है। यह नीति थी प्रकाश सिंह बादल, सुशील मुनि जैन और ग्रंथियों के माध्यम से उनसे (आतंकवादियों से) सौदा करने की। ऐसी उम्मीद थी कि अकालतखत के जत्थेदार यदि तमाम आतंकवादी संगठनों को नहीं तो अधिकांश को गोलबंद करने में सफल होंगे। फिर उनसे किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है। जैसी कि आलोचकों की भविष्यवाणी थी, उम्मीदें नाकाम साबित हुईं। अकालतखत के जत्थेदार को और अधिक समय दिया जाता और इससे और कत्लवगारत होती, यदि विर्क पर हुए हमले ने अभियान के लिए प्रेरित न किया होता। इस बीच काफी क्षति हुई। सौदा करने के प्रयास की नीति और कुछ नहीं, बल्कि असली लड़ाई को धीमा करने की एक नीति बनकर रह गयी थी। यह आतंकवादियों को पुनः संगठित करने, अक्तूबर-नवंबर १९८७ में हुई अपनी क्षतियों की भरपायी करने और सीमा पार से अधिक हथियार लाने में सहायक सिद्ध हुई और एक जनवरी, १९८८ से उन्होंने एक नया व बड़ा हमला शुरू कर दिया।

जैसा कि स्पष्ट है आपरेशन थंडरबोल्ट-२ को अच्छी कामयाबी मिली, किंतु यह आतंकवादियों की कमर नहीं तोड़ सका है। अनेक आतंकवादी बाहर थे। बहुतेरे स्वर्ण मंदिर से नहीं, बल्कि मांड क्षेत्र से अपनी कार्रवाइयां चला रहे थे। पंथिक समिति भी पूर्णतया एकजुट है। कमर तोड़ना अभी बाकी है, यह उनके (आतंकवादियों) द्वारा जारी हत्याओं के मौजूदा नये दौर से उजागर है। यह दरअसल तब हुआ, जब उन्हें अहसास हुआ कि सिख जनता उनकी मदद करने नहीं आ रही है। कुछ भी हो, इसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना तथा साथ-ही-साथ राजनीतिक मोर्चे पर सही पेशकदमी करना लाजिमी है।

हमारे विचार से इसमें इन कदमों को शामिल करना चाहिए:

- मांड क्षेत्र से आतंकवादियों की सफाई करना, सीमा को कारगर ढंग से सील करना और समुचित प्रबंधों द्वारा यह सुनिश्चित करना कि स्वर्ण मंदिर पुनः आतंकवादियों के कब्जे में न जा सके।
- आतंकवादियों से समझौता वार्ता की वर्तमान नीति को त्यागना और उनसे तभी बातचीत चलाना, जबकि वे हत्याएं बंद करके भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांतों को स्वीकार करें।
- गंभीर आरोपों से रहित जोधपुर नजरबंदों सहित तमाम निर्दोषों की रिहाई, सिख विरोधी दंगे आयोजित करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई—शुरुआत में सज्जनकुमार को कठघरे में खड़ा करके रखना।
- सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तमाम राज्यों को अधिक अधिकार दिया जाना। इसी के अनुसार पंजाब को भी अधिक अधिकार प्रदान करना, किंतु कोई ऐसा विशेष दर्जा न देना, क्योंकि इससे भारत के अंदर धार्मिक राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे समूचे देश में धर्मनिरपेक्षतावाद के सर्वनाश की छायाएं घिर आयेंगी।
- तमाम पार्टियों की मिलीजुली बैठक में पंजाब के मसले मसलन क्षेत्रीय और नदी पानी विवादों पर एक राष्ट्रीय आम सहमति विकसित करना, समस्त राष्ट्रीय पार्टियों और उनकी राज्य इकाइयों को इस आम सहमति को मानना। सभी पार्टियों को ऐसे कदम उठाकर सिखों को यह भरोसा दिलाना कि उनके धार्मिक अधिकार भारत में पूरी तरह सुरक्षित हैं। सिखों के एक भाग में फैली इस धारणा का—भले ही वह गलत क्यों न हो—कि वे समान नागरिक नहीं हैं, दूर करने के कदमों पर विचार करना। इस संबंध में जारी गलत प्रचार की काट के तरीकों और रास्तों को तलाश करना। भारत सरकार भी सच्चे धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम करे और राजकीय कार्यक्रमों में हिंदू कर्मकांड आदि बंद करे। शासक पार्टी भी हिंदू तुरुप का पत्ता चलकर अगले जीतने की कोशिश में लगाम लगाये। निश्चय ही राज्य सरकारों पर भी लागू हो, जिसमें पंजाब की कोई भी अकाली सरकार तथा साथ ही आंध्र प्रदेश की तेलुगू देशम सरकार शामिल है। जनमत को ऊंचा उठाकर इतना सुदृढ़ बनाना, जिससे कोई भी पार्टी अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग न करे।
- आतंकवादियों के हथियारों का निशाना खासकर अब पंजाब के आप्रवासी मजदूर बनने शुरू हो गये हैं। उनकी चाल है कि बदले की भावना से सिख विरोधी हिंसा हो और वे पंजाब के कुछ सिखों का समर्थन पुनः प्राप्त कर लें। उनकी इस मंशा को विफल करना है।
- वामपंथी और अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा पंजाब में कार्यकर्ता स्तर पर एक नया और व्यापक जन-अभियान चलाया जाना। ■

शिवसेना का दबदबा खतरे के निशान पर

औरंगाबाद कारपोरेशन के चुनाव में शिवसेना ने अन्य सभी पार्टियों को पछाड़ दिया था, लेकिन महापौर और उपमहापौर क्रमशः कांग्रेस-इ और मुस्लिम लीग के प्रत्याशी चुने गये। क्या ईद के एक दिन पूर्व औरंगाबाद में भड़के दंगों की वजह यही थी? शिवसेना की बढ़ती ताकत का राज क्या है और आम जनमानस में इसकी कैसी प्रतिक्रिया हो रही है?

महाराष्ट्र में ईद की पूर्व संध्या से लगभग एक हफ्ते तक चलता रहा सांप्रदायिक उन्माद का खूनी दौर करीब १६ लाख रुपए की संपत्ति को खाक़ में मिलाकर और कम-से-कम २६ लोगों को मौत के हवाले कर फिलहाल शांत हो गया है। लेकिन वह एक ओर जहां व्यापक स्तर पर तनाव बढ़ने-फैलने की गुंजाइश छोड़ गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के लिए एक जटिल और दीर्घकालिक राजनीतिक संकट का मुद्दा भी बन गया है। यह मुद्दा मुख्यमंत्री एसबी चव्हाण और दंगे के लिए जिम्मेदार बतायी जा रही शिवसेना, दोनों के भविष्य से भी जुड़ गया है।

इंसानियत पर दरिंदगी थोपने की हर साजिश की तरह यह दंगा भी सुनियोजित था। इसका लक्ष्य था जनसामान्य में क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता की जहरीली आग भड़का कर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना। इस सांप्रदायिक युद्ध का अखाड़ा बना राज्य का संवेदनशील नगर औरंगाबाद। पृष्ठभूमि में था; वहां का कारपोरेशन चुनाव। पंजाब की तरह महाराष्ट्र में आतंक को राजनीतिक औजार बनाने के लिए बराबर अखबारी सुर्खियों में रही शिवसेना ने बंबई और थाणे के बाद इस बार औरंगाबाद नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस-इ को उखाड़ दिया। उसने ६० में से २७ सीटें जीत लीं। सत्ताधारी कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय साबित हुई कि पार्टी का अंदरूनी कलह सड़क पर आ गया। दूसरी तरफ इस जीत ने शिवसेना में पूरा हिंदुस्तान फतह करने का हौसला जगा दिया और आम शिवसैनिक की जबान पर बुलंद होने लगा यह मराठी नारा:

"काल ठाणे मुंबई आणि औरंगाबाद, उदया संबंध महाराष्ट्र आणि मग हिंदुस्तान।" (बीते कल थाणे, बंबई और औरंगाबाद की बारी थी, आगामी कल पूरे महाराष्ट्र और भारत की बारी होगी।)

माहौल की आग: औरंगाबाद कारपोरेशन के चुनाव में शिवसेना की कामयाबी पर दलित मुस्लिम महासभा के नेता और ठाकरे के आलोचक हाजी मस्तान ने व्यंग्य किया था, "धन से घोड़ी दौड़ती है।" वोट के लिए की गयी मजहबी नारेबाजी की उन्होंने तीखी निंदा की और कहा, "जब धन और धर्म की खिचड़ी पकाई जाती है तब वह बेहद जहरीली होती है।" जब उनका ध्यान हाल के चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग के समर्थन की ओर खींचा गया, तो वह बोले, "समझदार मुस्लिम संगठन शिवसेना से दूर रहते हैं। लेकिन इस मामले में शिवसेना को वोट देने वालों का कुछ-न-कुछ स्वार्थ सधने वाला था। किसी को लाइसेंस की दरकार थी, तो किसी को कालेज में दाखिले की...।" कारपोरेशन का चुनाव शिवसेना ने 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का नारा देकर लड़ा था और उसकी जीत इस सच को उजागर करती है कि वह हिंदू भावना को उभाड़ने तथा अपने पक्ष में लाने में कामयाब रही। किंतु कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पायी। वह मौके की ताक में बैठी थी। शिवसेना के चुनाव जीतने से तनाव भी बढ़ गया था और प्रशासन को नगर में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। इस माहौल में, २ मई को कारपोरेशन के मेयर का चुनाव हुआ। पार्षदों के चुनाव के दौरान शिवसेना ने दलितों और मुसलमानों के खिलाफ खूब बका-झका था, लिहाजा इन दोनों समुदायों के पार्षद नाराज थे। मेयर के चुनाव में इन पार्षदों ने न सिर्फ अपना ही समर्थन कांग्रेस को दिया, बल्कि अन्य समुदायों के पार्षदों को भी अपने साथ खींचने की भरपूर कोशिश की। फलतः कांग्रेस के डा० शांताराम काले मेयर चुने गये। उपमहापौर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को बनाया गया।

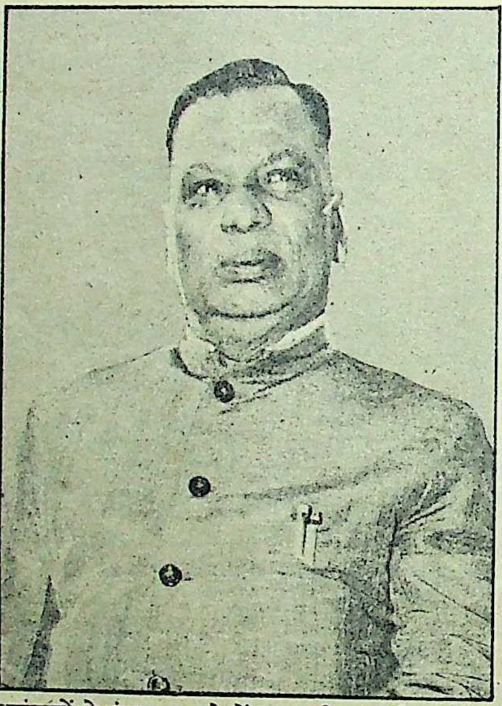

असंतुष्टों ने दंगा भड़काने में मदद दी: एसबी चह्वाण

राजनीतिक संकट का जायजा: शीला कौल

शिवसेना को इस नतीजे की भनक बहुत पहले मिल गयी थी। इसलिए पहले तो उसने मेयर के चुनाव का बहिष्कार कर अपनी हार टालनी और इज्जत बचानी चाही। बाद में उनके एक पार्षद ने बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में एक याचिका दायर कर महापौर के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी। याचिका की सुनवाई १७ मई को थी। इस मौके पर भारी संख्या में न्यायालय पहुंचे शिवसेना-समर्थक देर तक नारेबाजी करते रहे और जोर देकर कहते रहे कि सुनवाई आगे न टाली जाये। लेकिन खंडपीठ ने मामले की सुनवाई २४ मई तक टाल दी। बस

माहौल गरमा गया। अदालत से वापसी के दौरान शिवसेना समर्थकों ने विशाल जुलूस निकाला और भड़काने वाले नारे लगाये। इसके बाद जो होना था सो हो गया। पथराव, आगजनी, छुरेबाजी, दुकानों की लूटपाट का शैतानी सिलसिला शुरू हो गया। देखते-देखते दंगा आसपास के गांवों में भी फैल गया और अगले कुछ दिनों में तो उस्मानाबाद, जालना आदि पड़ोसी जिले भी इसकी चपेट में आ गये। बर्बरता का यह नंगा नाच चार-पांच दिनों तक चलता रहा। २६ बेकसूर इंसान हलाल कर दिये गये, दर्जनों लोग घायल हुए, सोलह लाख रुपए की संपत्ति आग के हवाले कर दी गयी।

जोड़-तोड़ जारी : औरंगाबाद और आसपास के दंगों के मूल में शिवसेना द्वारा भड़काया गया सांप्रदायिक उन्माद तो था ही, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और प्रशासन की खामी भी उतनी ही जिम्मेदार थी। महाराष्ट्र की कांग्रेसी राजनीति में हाल के महीनों में जोड़तोड़ की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक तेज रही है। एक ओर मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण ने अपनी नीतियों के कारण पार्टी की गन्ना लाबी को नाराज कर दिया है, दूसरी ओर, शरद पवार पार्टी आलाकमान की उपेक्षा से चिढ़े हुए हैं। (उल्लेखनीय है कि १९८० और '८४ के चुनावों में कांग्रेस की लहर के बावजूद पवार ने अपने बूते विधानसभा की ५४ सीटें जीती थीं। लेकिन दिल्ली की ओर से उपेक्षा होने के कारण उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।) उधर महाराष्ट्र में 'गन्ना लाबी' के हितों की रक्षा करनेवाले पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल भी राजस्थान छोड़कर बंबई में अड्डा जमाये हुए हैं और नेतृत्व बदलने का अभियान चला रहे हैं। निगम के चुनाव में पार्टी की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण भारी संख्या में विद्रोही इंका प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना भी रहा है। जिससे अधिकृत उम्मीदवारों के वोट कई हिस्सों में बंट गये। इस जोड़तोड़ की राजनीति ने मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी बचाने तक ही सीमित कर दिया। इस कारण वे न तो कारपोरेशन के चुनाव में पार्टी को कामयाबी दिलाने में समर्थ हो सके और न दंगों पर शीघ्र काबू पाने की तत्परता दिखा सके। यह बात दंगों पर टिप्पणी के दौरान उनके उस बयान से जाहिर होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशासन को दंगे होने का शक पहले ही से था। सवाल उठता है कि इस शक के बावजूद प्रशासन ने दंगे रोकने की तत्परता क्यों नहीं दिखाई? जाहिर है शंकर राव चव्हाण मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रहे दंगे को टालने में अधिक व्यस्त थे।

आलाकमान की उपेक्षा से क्षुब्ध : शरद पवार

गन्ना लाबी के संरक्षक : वसंत दादा पाटिल

उधर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का आरोप है कि कांग्रेस स्वयं दंगा कराना चाहती थी, ताकि अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाती जा रही शिवसेना को बदनाम किया जा सके। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांप्रदायिक तनाव को खुलकर बढ़ावा दिये जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा है, "असंतुष्टों ने मुझे हटाने के लिए दंगा भड़काने में शिवसेना की मदद की, ताकि आलाकमान को समझाया जा सके कि शिवसेना के प्रभाव से पार्टी को बचाने के लिए चव्हाण को हटाना जरूरी है।"

महाराष्ट्र कांग्रेस की अंदरूनी उठा-पटक का अभियान अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दोनों गुटों के लोग आलाकमान के समक्ष अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने में जुटे हैं। आलाकमान महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को भांप चुका है। पार्टी की नयी महासचिव शीला कौल के दो दिन के बंबई दौरे का उद्देश्य इसी संकट का जायजा लेना है।

असली खतरा : दंगे के कारणों में एक बात और बतायी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से शिवसेना स्थानों के नाम बदलने का अभियान चला रही है। शुरुआत उसने बंबई का नाम बदलकर 'मुंबई' करने की मांग के साथ की। फिर उसने औरंगाबाद शहर का नाम 'खड़की' करने की मांग की। (समझ में नहीं आता कि हिंदू नारे देने वाली शिवसेना को औरंगजेब के बहुत पहले मलिक अंबर द्वारा अपने अज़ीज गुलाम मोहम्मद हसन खड़की के नाम पर बसाये गये इस शहर का यह मुस्लिम नाम कैसे भा गया!) इसी प्रकार शिवसेना ५६ और नाम बदलना चाहती है, जिनमें अनेक मुस्लिमबहुल स्थान भी हैं, जहां सांप्रदायिक भावनाओं का भड़कना स्वाभाविक है। इस अभियान की प्रतिक्रिया औरंगाबाद ही नहीं, बल्कि उस्मानाबाद, नांदेड़, लातुर, जालना, परमनी आदि जिलों में भी हो सकती है। इससे स्थिति उग्रतर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे एक अरसे से महाराष्ट्र सांप्रदायिकता की बदबूदार उत्तेजना से भरा हुआ है। भिवंडी के दंगों का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। यहां तक कि जलगांव जैसे शांत क्षेत्र पर भी सांप्रदायिकता की सनक हावी है, जहां पिछले चार-पांच वर्षों में ३५ घटनाएं हुई हैं। पूना भी तनावग्रस्त है। ऐसे में सांप्रदायिकता की धीमी हवा भी किसी भी क्षेत्र में आग भड़कने का कारण बन सकती है।

कारपोरेशन चुनाव और हाल के दंगे महाराष्ट्र में शिवसेना के बढ़ते वर्चस्व के ताजा गवाह हैं। दोनों घटनाएं बताती हैं कि अभी दो वर्ष पहले तक केवल मराठा जजबात की राजनीति करती रही शिवसेना अब राज्य में हिंदू भावना को भी भड़काने में सक्षम है—महाराष्ट्र और भारत-विजय का उसका मंसूबा निहायत बेबुनियाद नहीं है। इस देश के बनने-बिगड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य (महाराष्ट्र) का इस वक्त अहम मुद्दा यही है। इसी मुद्दे से राज्य के लोग परेशान हैं और आतंक के साये में संतुलन खोकर 'भिंडरांवाले' का तुक 'बांदरावाले' से मिलाने लगे हैं। (बंबई को जाननेवाले लोग बांदरा को भी जानते हैं : यह बंबई नगर का वह हलका है जहां शिवसेना प्रमुख बालासाहब केशव ठाकरे का आवास है।) तुक मिलानेवाले लोग ठाकरे की 'खतरनाक छवि' उभारने के लिए उन्हें और इनकी सेना को कई तरह के नामों से प्रचारित कर रहे हैं मसलन हिंदू पुनरुत्थानवादी, आतंकवादी, लुटेरे, सीआईए के एजेंट आदि। मगर असली खतरा यह है कि इंकाई सेना पर शिवसेना भारी पड़ रही है और परंपरागत राजनीति का समीकरण ही गड़बड़ा गया है। इसलिए इन प्रचारों की बदौलत ठाकरे और शिवसेना के वर्चस्व को बढ़ावा मिल रहा है। साफ है कि अगर शिवसेना की लोकप्रियता बखूबी बढ़ रही है तो ठीक इसके उलटे इंका 'एक पुराना सवाल' बनती जा रही है तथा विपक्ष और इंका दोनों के लीडरान शिवसेना से अच्छे ताल्लुकात रखने लगे हैं।

राज्य और राष्ट्र तो क्या, पूरी दुनिया के लिए भी शिवसेना अब कोई नया नाम नहीं रह गयी है। नयी चीज यह संतुलन खोना ही है और यह भी कि लोग बदहवासी के दौर से गुजर रहे हैं।

—परम सकलेचा

साक्षात्कार : **बालासाहब ठाकरे**

पहली योजना महाराष्ट्र पर कब्जा करना है।

हिंदू सांप्रदायिकता के जरिये महाराष्ट्र की राजनीति में खतरनाक ढंग से पांव पसारने वाली शिवसेना के मुखिया बाल ठाकरे के विषाक्त विचारों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद में दंगे क्यों भड़के। वह धर्म निरपेक्ष देश में जिस हिंदूवाद की उग्र वकालत कर रहे हैं, उससे केवल महाराष्ट्र को ही खतरा नहीं, बल्कि पूरे देश को है। शिवसेना की मानसिकता को समझने के लिए 'माया' ने कार्टूनिस्ट से दुर्घर्ष राजनेता बनने जा रहे बाल ठाकरे से बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश :

माया : औरंगाबाद नगर निगम चुनावों में सफलता के बाद अगली मंजिल कौन-सी है?

ठाकरे : यह इस पर निर्भर है कि कांग्रेस-इ हमें क्या-क्या जरूरी साजसामान सप्लाई करती है। मैं तो बस एक हिंदू का अपना कर्तव्य पूरा करता हूं।

माया : किंतु शिव सेना के लिए आपकी कोई योजना तो अवश्य होगी।

ठाकरे : पहला, महाराष्ट्र में सत्ता पर कब्जा करना। यह एक सौ एक फीसदी तय है। और एक फीसदी आप अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। मेरी विजय में रत्ती भर संदेह नहीं।

माया : क्या इसका आगामी जिला परिषद चुनावों से श्रीगणेश होगा?

ठाकरे : (हंसकर) श्रीगणेश पहले ही हो चुका है। हमारी शानदार शुरुआत पार्ले उपचुनाव से हुई, फिर औरंगाबाद का नंबर आया जो हमारे लिए विजय द्वार सिद्ध हुआ है।

माया : क्या आप हिंदू अंधराष्ट्रवाद व कट्टरतावाद का अपना तुरुप का जो पत्ता बराबर व ऐलानिया चल रहे हैं, उसका मकसद अधिक वोट बटोरना है?

ठाकरे : इसमें हर्ज क्या है? यह देश हिंदुओं का है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मुझे यह पत्ता खेलना पड़ता है। यह मेरा देश है, हम हिंदुओं का देश है। पाकिस्तान में आपको ऐसा पत्ता खेलने की जरूरत नहीं। वे ऐलानिया कहते हैं कि वे मुस्लिम हैं और उनका एक इस्लामी राष्ट्र है। बदकिस्मती से यहां हमें इस बात पर बल देना पड़ता है, क्योंकि हमारी 'सर्वधर्म समभाव' व 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' जैसी बेवकूफी की नीतियां हैं। इनका सर्वनाश हो। मेरा ऐसे नारों में विश्वास नहीं।

माया : फिर आपका क्या कहना है?

ठाकरे : मेरा कहना है कि हिंदू धर्म की कीमत पर कुछ नहीं होना चाहिए।

माया : अन्य तथाकथित हिंदू नेता ऐसा ही क्यों नहीं सोचते?

ठाकरे : वे मुस्लिम वोटों के गुलाम बन गये हैं। मैं मराठी में कहता हूं कि वे 'लाचार' हैं।

माया : क्या आपका इस वोट बैंक को भारत से दूर करने का कोई सुझाव है?

ठाकरे : उनका अपना बैंक और जमा खाता होना चाहिए और हमारा अपना। यदि ऐसा नहीं है, तो हमें हिंदू वोट बैंक बनाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। यह एक ऐसी चाल होगी जिससे मौजूदा मुस्लिम लाड़-प्यार पर रोक लगेगी।

माया : शिव सेना असल में चाहती क्या है?

ठाकरे : लोगों के हमारे संगठन के बारे में बड़े भ्रामक विचार हैं। वे हम पर प्रतिवाद, अंधराष्ट्रवाद, कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। यह सब बकवास है। मुझे इन आरोपों की परवाह नहीं। हमारा आधार महाराष्ट्र में तीन वर्ष पूर्व बना था। यद्यपि लोगों ने यह कहकर हमारा उपहास किया था कि यह चंद उखड़े लोगों का टीमटाम है। किंतु हमने अब इसे गलत सिद्ध कर दिया। हमने बुनियादी काम काफी समय पूर्व कर लिया था। अब हम अपने श्रम को फलता-फूलता देख रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता प्रधान संगठन है जो सही दिशा में राष्ट्र और उसकी जनता की महान सेवा कर रहा है। लोगों को धीरे-धीरे हमारी कीमत का पता चल रहा है।

माया : विषयांतर के लिए क्षमा करेंगे, किंतु आप तो प्रायः पाइप पीते थे, अब सिगार क्यों?

ठाकरे : (हंसकर) मैं हर चीज पीता हूं। आपको धुंए से मेरे संबंधों का पता है?

माया : नहीं।

ठाकरे : यदि कहीं कोई चीज जलती है तो शिव सेना को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

माया : आरोप है कि आपके संगठन को सीआईए व पाकिस्तान से आर्थिक सहायता मिलती है?

ठाकरे : यह बड़ी दूर की कौड़ी है। मैं चाहता हूं कि सीआईए हमें धन दे, किंतु हम पाकिस्तान से पैसा नही चाहते।

माया : तर्क यह है कि पाकिस्तान यह साबित करना चाहता है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और मुसलमानों को दबाया जाता है। इसीलिए आपको धन दिया जाता है, ताकि आप उत्पात मचा सकें।

ठाकरे : प्यारे भाई! क्या आप यह आसान बात नही समझते कि हिंदुत्व की वकालत करनेवाला व्यक्ति क्या 'हरा' धन कभी छुएगा? हम ऐसी सिद्धांतहीन बातों में नहीं पड़ते। हिंदूवाद की इस विशेष विचारधारा के प्रचार-प्रसार का क्या महत्व रह जायेगा, यदि उसे पाकिस्तानी धन पर निर्भर रहना पड़े। यह सब बकवास है।

माया : शिव सेना की महाराष्ट्र के बाहर क्या स्थिति है?

ठाकरे : मुझे उ०प्र० के लोगों ने बुलाया है और वहां मैं जा भी रहा हूं। उन लोगों का कहना है कि मेरी सभा राजीव गांधी की हाल की सभा से भी बड़ी होगी।

माया : शिव सेना के आतंक राज के बारे में आपका क्या कहना है?

ठाकरे : यह आतंक राज क्या बला है?

माया : जबरन पैसा-वसूली। मसलन, गणपति समारोहों के लिए, काम कराने के लिए, और मामला निपटाने के लिए?

ठाकरे : सरकार क्या कर रही है? यदि शिव सेना किसी से जबरन धन वसूलती है या अमरीका व पाकिस्तान से आर्थिक सहायता लेती है, तो गुप्तचर विभाग तो है। शायद मैं दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति हूं, तभी तो महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकारें होने के बावजूद इस तरह की मदद प्राप्त कर रहा हूं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वे शासन करने के योग्य नहीं।

माया : यह अफवाह है कि श्रीमती गांधी की हत्या के तुरंत बाद बंबई के सिखों की रक्षा की पेशकश आपने अपनी एक मांग के तहत की

थी, जिसमें आपको १२ लाख रुपए मिले थे?

ठाकरे: १२ लाख? (व्यग्य सहित) वाह! मैं इतना सस्ता नहीं हूं। सिखों और पत्रकारों के बीच एक प्रेस कांफ्रेंस में मैंने सिख नेताओं से दो टूक सवाल किया था, "क्या मैंने कभी आपको ब्लैकमेल किया था; जिसके लिए आपने मुझे भारी रकम अदा की थी? यदि आपने मुझे एक पैसा भी दिया हो, तो उसे प्रेस के सामने घोषित करें।" उन सबने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ।

माया: आपने सिखों के बहिष्कार के अपने आह्वान को वापस क्यों ले लिया?

ठाकरे: मैंने वापस नहीं लिया। मैं अभी स्थिति देख-परख रहा हूं।

माया: किस कारण से आपने बहिष्कार का नारा दिया था?

ठाकरे: जब मैंने नारा दिया था, तो मेरे दिमाग में धनी सिख थे, पूरा सिख समुदाय नहीं था। इसके अलावा यह आर्थिक बहिष्कार था, सामाजिक नहीं, जैसा प्रेस ने अर्थ लगाया है। विपक्षी पार्टियों और कुछ सिखों ने उस बयान को एक प्रचार-औजार के रूप में मनचाहा रंग दिया, जिससे सिख वोट हथिया सकें। यह सब राजनीति का खेल है। यह ऐसा घृणित रोग है, जिससे यह देश ग्रस्त है। इसका कोई इलाज नहीं दिखाई देता। उन लोगों ने मेरे नारे के संदर्भ में बड़ा 'गंदा खेल' खेलते हुए उसे तोड़ा-मरोड़ा और तिल का ताड़ बनाया। जबकि मैं बारबार कहता रहा कि यह नारा पूरे समुदाय के लिए नहीं उन धनिकों के खिलाफ है जो कि इस विशेष खालिस्तानी आंदोलन को निश्चित रूप से आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता मुहैया करते हैं।

माया: मुख्यमंत्री एस०बी० चह्वाण ने आपके नारे के खिलाफ जो प्रतिक्रिया की है उस पर आपका क्या मत है?

ठाकरे: श्री चह्वाण ने कहा है कि यदि एक भी सिख परिवार महाराष्ट्र छोड़ता है, तो यह उनकी व्यक्तिगत हार होगी। मैं नहीं समझता कि वह शहीद या हीरो क्यों बनना चाहते हैं। क्या यही सज्जन उस समय केन्द्रीय गृहमंत्री नहीं थे जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी और उस समय ढाई हजार से ज्यादा सिखों की दिल्ली में हत्या हुई थी और ५० हजार सिख दिल्ली छोड़कर पंजाब में जा बसे थे? उस समय यह आदमी क्या कर रहा था? क्या यह सब उनके निर्देश पर हुआ था? या उससे महज टुकुर-टुकुर ताकने और होंठ सिलने को कहा गया था? मेरा कहना है कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके भारत के गृहमंत्री रहते हुए यह कत्लेआम और पलायन हुआ था।

माया: इस घटना के अतिरिक्त श्री चह्वाण के बारे में आपकी क्या राय है?

ठाकरे: वह देश के निकृष्टतम मुख्यमंत्री हैं।

माया: वसंत दादा पाटिल के बारे में आपका क्या मत है?

ठाकरे: वह सौम्य और शिष्ट व्यक्ति हैं। उनमें एक प्रकार की प्रौढ़ता है।

माया: और शरद पवार?

ठाकरे: वह राजनीति के गुंडे हैं क्योंकि उनका एकमात्र मकसद सत्ता हथियाना है। वह गद्दी पर बैठने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते।

माया: अंतुले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

ठाकरे: उनकी जाति, धर्म को भूल जाइये। वह चटपट फैसला लेनेवालों में हैं। इस मामले में वह सचमुच लाजवाब हैं।

माया: उनके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बारे में आप कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

ठाकरे: वह एक फैसला है। हमारी न्यायव्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। हां, फांसी के मामले में राष्ट्रपति जरूर अपने अधिकार का प्रयोग क्षमादान के लिए कर सकता है। निर्णय अंतिम सत्य है, जिसे मानना चाहिए।

माया: कांग्रेस-इ के विषय में आपका एक दोहरा चरित्र तब उजागर हुआ जब अमिताभ बच्चन और शहंशाह के मसले पर आपका नर्म रुख दिखायी पड़ा तथा उस फिल्म के रिलीज होने में आपने मदद तक पहुंचायी।

ठाकरे: मेरे सामने दो बातें थीं। पहली, अमिताभ की अन्य फिल्मों को बंबई में चलने देने की इजाजत संबंधी दोहरा मानदंड, क्योंकि यदि आपने अमिताभ विरोधी ऐसा कड़ा रवैया अपनाया है, तो आपको चाहिए कि आप उनकी एक भी फिल्म पर्दे पर चलने या रिलीज होने न दें। दूसरी, यदि आप व्यक्ति पर हमला करना चाहते हैं, तो उसके राजनीतिक व्यक्तित्व पर करें, एक कलाकार पर नहीं। मैं यह चाहता था कि उनको एक कलाकार और अभिनेता के रूप में सम्मान मिले। आप दोनों (राजनीतिज्ञ व कलाकार) को मिला नहीं सकते। यह पेट पर लात मारना है जो गंदी राजनीति है। फिर अमिताभ को पहले ही अपने किये का फल मिल चुका है। किंतु गरीब निर्माताओं और वितरकों को क्यों मुसीबत झेलनी पड़े? अंततः हुआ क्या? आंदोलन टांय-टांय फिस्स हो गया। जैसा मैंने कहा कि यह गंदी राजनीति थी। किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं। मैं इस गंदी चरित्र-हत्या का प्रशंसक नहीं। मैं जानता हूं कि चंद भ्रष्ट क्रियाकलाप जारी हैं, किंतु हथौड़े का वार करके मक्खियां मारने की कोशिश क्यों की जाये। यह तो तभी जायज होगा, जबकि आपके पास अकाट्य सबूत हों।

> सरकार क्या कर रही है?
> यदि शिव सेना किसी से जबरन धन
> वसूलती है या अमरीका व पाकिस्तान
> से आर्थिक सहायता लेती है, तो
> गुप्तचर विभाग तो है।
> शायद मैं दुनिया का सबसे चतुर
> व्यक्ति हूं, तभी तो महाराष्ट्र और
> दिल्ली में सरकारें होने के बावजूद
> इस तरह की मदद प्राप्त कर रहा हूं।

माया: कार्टूनिस्ट व्यंग्यकार होना कैसा लगता है?

ठाकरे: यह एक विलक्षण अनुभूतियोंवाली कला है। यदि मैं कार्टूनिस्ट न होता, तो अन्य राजनीतिज्ञों की भांति दुष्ट होता। मैं राजनीतिक कार्टूनिस्ट पहले हूं और अपने पत्ते कैसे खेले जाते हैं, इसकी मुझे जानकारी है।

माया: क्या आप वीपी सिंह के चमत्कारी व्यक्तित्व पर टिप्पणी करेंगे?

ठाकरे: उनका प्रभाव केवल उ०प्र० तक सीमित रहेगा। मैं नहीं समझता कि पूरे देश पर उनकी पकड़ है।

माया: क्या उनका भ्रष्टाचार से मुक्त होने का दावा ठीक है?

ठाकरे: वह एक राजा थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि वह दूसरों की तरह लालची हैं। किन्तु उन्हें इसका पूरा एहसास है कि इस देश में चुनावों की क्या कीमत है। और उसे लड़ने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार के दलदल में उतरना ही पड़ेगा। बिना भ्रष्टाचार के आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। कम-से-कम संसद का। राजनीति भ्रष्ट लोगों का खेल है।

माया: भारत की विदेश नीति खासकर श्रीलंका-पाकिस्तान के संदर्भ में आपकी राय क्या है?

ठाकरे: ये दो चीजें हैं। पाकिस्तान की हमारी बुरी विदेश नीति है और श्रीलंका की बदतरीन।

माया: आपकी इस बात का आधार क्या है?

ठाकरे: सरकार ने मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है। कोई भी देश दूसरे देश के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा, जैसा हमने किया है। क्या तमिल चीतों से लोहा लेने के लिए श्रीलंका की अपनी सेनाएं नहीं हैं? हमने पहले बांगलादेश में 'कंचनजंगा' जैसी भूल की थी और अब श्रीलंका में हिमालय जैसी भूल की है।

—संजय ए० सयानी

अब कलह एनएसयूआई में

बिहार में मुख्यमंत्री और विधानसभाध्यक्ष, राजस्थान में हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर तथा मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह, सिंधिया और वोरा ही आपस में नहीं टकरा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस-इ के अन्य संगठनों में भी खुला संग्राम चल रहा है। हाल में एनएसयूआई (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन) की दिल्ली इकाई में दिल्ली छात्र मोर्चा के विलय और उसके बाद दिल्ली इकाई को भंग करने के कारण चल रहा संघर्ष इसका उदाहरण है। एनएसयूआई की दिल्ली इकाई के संकट को जन्म देने वाली परिस्थितियों का आकलन :

राजधानी की सातों संसदीय सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से तीन सांसद (भगत, टाइटलर और पंत) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और एक (अर्जुन सिंह) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किंतु दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खुद कितने पानी में है, इसकी मिसाल उसके छात्र संगठन एनएसयूआई (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन) के दिल्ली प्रदेश इकाई में आया हाल का संगठन) की दिल्ली प्रदेश इकाई में आया हाल का के छात्र सगठन विद्यार्थी परिषद का वर्षों से बोलबाला रहा है। उससे मैदान मारने की कांग्रेस की पहल का पहला चरण ही गत माह तब लड़खड़ाता दिखायी दिया, जब एनएसयूआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश सब्बरवाल सहित सात जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मजे की बात तो यह है कि अन्य विवाद तो दरकिनार, यह इस्तीफा-प्रकरण ही विवाद का मुद्दा बन गया है। एक ओर एनएसयूआई अध्यक्ष मनीष तिवारी ने १९ अप्रैल को अध्यक्ष रमेश सब्बरवाल सहित प्रदेश इकाई को भंग करने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष सब्बरवाल का दावा है कि न केवल उन्होंने, बल्कि उनके साथ सात जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने इस्तीफों की पेशकश पार्टी के महासचिव और छात्र मामलों के प्रभारी आस्कर फर्नांडीस को १३ अप्रैल को ही कर दी थी। जानकार सूत्रों के अनुसार फर्नांडीस के सामने जब इस्तीफे की पेशकश की गयी, तो उस समय वह उत्तर-पूर्व राज्यों के दौरे पर जा रहे थे। उन्होंने सब्बरवाल तथा अन्य पदाधिकारियों को जल्दबाजी में कदम न उठाने की सलाह देते हुए कहा कि लौट कर आने पर वह मामले को सुलझायेंगे। १८ अप्रैल की देर रात की अपनी बैठक में उन्होंने सब्बरलाल को आश्वासन दिया कि वह सुलह-सफाई का प्रयास करेंगे और मामले को तूल न पकड़ने देंगे। किंतु अगले ही दिन एनएसयूआई अध्यक्ष मनीष तिवारी ने समूची दिल्ली इकाई को ही भंग करके मामले को एक नया मोड़ दे दिया। विवाद केवल इस्तीफे देने या समस्त पदाधिकारियों को अपदस्थ करने का ही नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि कितनों ने इस्तीफा दिया।

मनीष तिवारी ने 'माया' से एक भेंट में बताया, "केन्द्रीय कार्यालय को आज तक किसी भी पदाधिकारी का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस्तीफों की बात करने वाले सरासर गलतबयानी कर रहे हैं।" इसके ठीक विपरीत दावा रमेश सब्बरवाल गुट का है। एक पूर्व पदाधिकारी ने अपने दावे की सचाई पेश करते हुए इस्तीफों की प्रतिलिपि 'माया' को दिखायी। उस पदाधिकारी का कहना था कि इस्तीफों की बात को झुठलाने वाले यह अनदेखा करना चाहते हैं कि हमने अपने इस्तीफे अपने सर्वोच्च पदाधिकारी और प्रभारी आस्कर फर्नांडीस को सौंपे हैं।

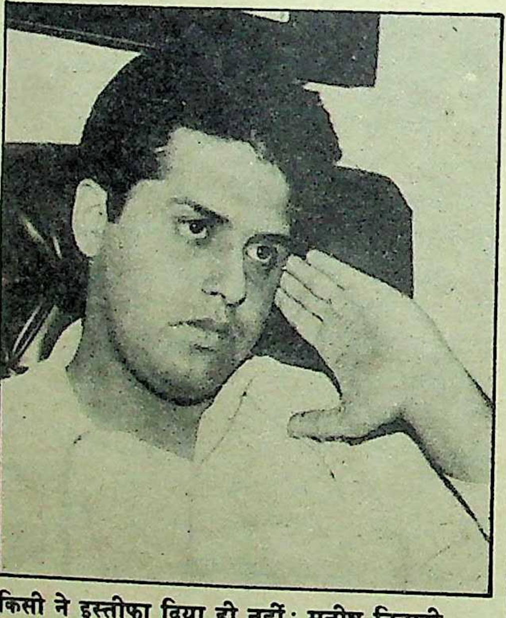

किसी ने इस्तीफा दिया ही नहीं : मनीष तिवारी

विलय से उपजा संकट : कलह की शुरुआत जनता पार्टी की तरह एक विलय से हुई। १३ अप्रैल को एनएसयूआई अध्यक्ष ने दिल्ली छात्र मोर्चे के विलय की घोषणा की। इसके तुरंत बाद विरोध का हंगामा खड़ा हुआ। जो दिनोदिन घटने के बजाय बढ़ता गया। दिल्ली एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि कल तक हमारे ही नहीं, हमारे शीर्षस्थ नेताओं पर कीचड़ उछालने वाले संगठन के विलय के बारे में हम लोगों से पूछा तक नहीं गया। उनके अनुसार और-तो-और दिल्ली छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों ने गत वर्ष मई के महीने में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का रामजस कालेज में पुतला जलाया था और बोफोर्स कांड के खिलाफ राष्ट्रपति जैल सिंह से प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए ज्ञापन देने का प्रयास किया था।

असंतुष्ट गुट का आरोप है कि अध्यक्ष मनीष तिवारी अपने कुछ खास लोगों के चक्कर में पड़कर धड़ाधड़ इकतरफा और उलटे-सीधे फैसले ले रहे हैं। उन पर आरोप मौजमस्ती करने के भी कुछ कम नहीं हैं। इसके तहत पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व देने के बजाय उनका लक्ष्य अपने खास गुट की जड़ें मजबूत करना है। यही कारण है कि छह साल से काम करने वाले कार्यकर्ता तो मुश्किल से जिलाध्यक्ष ही बन पाये हैं, किंतु विलय के मार्ग से आये लोगों को ऊंची कुरसी मिलने लगी है। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए असंतुष्ट संदीप सिंह का उदाहरण देते हैं, जिन्हें विलय के प्रथम दिन ही प्रदेश का महासचिव बनाने की घोषणा की गयी।

मनीष तिवारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने के पूर्व दिल्ली के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। इनमें एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, श्रीमती ताजदार बाबर आदि शामिल हैं। यही वजह है कि मामले ने दबने के बजाय तूल पकड़ा है।

इस विलय में भी पेंच है। दिल्ली छात्र मोर्चा का एनएसयूआई में यह दूसरा विलय है। पहला विलय पूर्व अध्यक्ष मुकुल वासनिक जो अब युवक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, के कार्यकाल में १९८७ के प्रारंभ में हुआ था। दूसरा विलय गत १३ अप्रैल को। किंतु रोचक बात तो यह है कि दो-दो बार विलय के बाद भी दिल्ली छात्र मोर्चा अलग संगठन के रूप में अभी भी बरकरार है। ज्ञात रहे, १९८६ में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के ऐन मौके पर ही दिल्ली छात्र मोर्चा बना था। उस समय भाजपा गुट से राजेश गर्ग और इंका गुट से मदन सिंह बिष्ट अध्यक्ष पद के प्रबल उम्मीदवार थे। दोनों पार्टियों ने इन दोनों को टिकट नहीं दिया। उसी दौरान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष वी रवीन्द्रन के नेतृत्व में दिल्ली छात्र मोर्चा का गठन हुआ और इसके

प्रत्याशी मदन सिंह बिष्ट छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गये। किंतु १९८७ के छात्र संघ चुनाव के कुछ महीने पूर्व ही ये तीनों एनएसयूआई में शामिल हो गये। बाद में मदन सिंह बिष्ट तो छात्र राजनीति में निष्क्रिय हो गये और वी रवीन्द्रन निर्दलीय अवधेश मिश्र को छात्र संघ का चुनाव लड़वाने के कारण संगठन से अलग हो गये। केवल राजेश गर्ग पिछले छात्र संघ चुनाव में पराजित होने के बावजूद एनएसयूआई के उपाध्यक्ष बनकर संगठन में कार्यरत हैं।

१९८७ के विलय के बावजूद दिल्ली छात्र मोर्चा के कप्तान सिंह और अश्विनी कुमार मोर्चा के नाम से काम करते रहे। गत छात्र संघ चुनाव में स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी से तालमेल करने के बावजूद इन्हें कोई सीट हाथ नहीं लगी। नतीजतन अश्विनी कुमार जनछात्र मोर्चा बना वीपी सिंह के जनमोर्चा से जुड़ गये हैं, कप्तान सिंह एनएसयूआई में शामिल हो गये हैं और दिल्ली छात्र मोर्चा को बनाये रखने का ठेका हरिमोहन के हाथ में जा पहुंचा है।

विलय और बरकरारी का यही आलम स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का भी है, जिसके नेता संदीप सिंह आज एनएसयूआई के पदाधिकारी बन गये हैं। उल्लेखनीय है कि यह संगठन पूर्व सांसद एफएम खान का है जो इंका में जाने की आस लगाये बैठे हैं।

चूंकि विलय का यह क्रम पहले ही जारी हो चुका था, इसलिए अध्यक्ष मनीष तिवारी इसके लिए अपने को दोषी करार नहीं देते। उन्होंने 'माया' से बातचीत में कहा, "जहां तक छात्र राजनीति का सवाल है, इसमें स्थायी वफादारी और निश्चित विचारधारा जरूरी नहीं होती। अत: जब कोई अपने किये पर पश्चाताप करता हुआ आने का अनुरोध करता है, तो उसे हम वापस ले लेते हैं। इस समय भी ठीक यही हुआ। हमें दाखिले की अर्जी मिली। विलय की पूर्व प्रक्रिया हमारे सामने थी, तो हम किस आधार पर उसे नामंजूर कर सकते थे?"

किंतु हाजिरजवाब असंतुष्ट गुट का कहना है, "यह सही है कि पहला विलय मुकुल वासनिक के कार्यकाल में हुआ था, किंतु पार्टी-विरोधी गतिविधियां उसके बाद उजागर हुईं और उसके सरगना कप्तान सिंह आदि को सरमाथे लेना कहां की अकलमंदी है?"

फर्नांडीस की सहमति: जहां तक विलय व पुन: प्रवेश का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष मनीष तिवारी को पार्टी महासचिव और प्रभारी आस्कर फर्नांडिस की पूरी सहमति प्राप्त है। आस्कर फर्नांडीस ने 'माया' को बताया, "प्रतिद्वंद्वी छात्र संगठनों के लोगों का हमारे संगठन में शामिल होना इस बात का संकेत है कि हमारी पार्टी लगातार प्रगतिपथ पर अग्रसर है। ऐसी हालत में यदि वे हमारे संगठन से जुड़ना चाहें, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है।" मनीष तिवारी के दिल्ली राज्य इकाई भंग करने पर रजामंदी दिखाते हुए आस्कर का कहना है, "एनएसयूआई के अध्यक्ष का सरोकार और अधिकार है कि वह देखे कि कौन अधिक कारगर और सक्षम है।"

प्रकारांतर से उनका संकेत मनीष तिवारी के इस कथन की पुष्टि करता है कि अक्षमता और अयोग्यता के कारण ही पदाधिकारियों सहित दिल्ली राज्य इकाई भंग की गयी है। मनीष तिवारी के अनुसार यह निर्णय उनका अपना नहीं, राष्ट्रीय समिति का है, जहां तमाम मसलों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श होता है और सर्वस्वीकृत फैसला लिया जाता है।

अक्षमता और अयोग्यता के आरोप के जवाब में पूर्व अध्यक्ष रमेश सब्बरवाल तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 'माया' से कहते हैं, "हम पर आरोप लगाने वालों को शायद अक्षमता और सक्षमता में भेद नहीं मालूम है। दिल्ली में आज तक कभी जिला, ब्लाक, विश्वविद्यालय और कालेज इकाई में एनएसयूआई नहीं पहुंचा था। हमने यह काम महज आठ महीने में पूरा कर दिखाया था। इसी दौरान हमने ५२ में से ४० कालेजों के छात्र संघों में विजय प्राप्त की। विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारिणी के १६ में से ९ सदस्य एनएसयूआई के हैं। यदि इस पर भी अक्षमता का आरोप लगाया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली राज्य इकाई भंग करने का मुख्य कारण यही है कि न हमने गलत कामों में साथ दिया और न किसी की चमचागिरी की।"

हम पर आरोप लगाने वालों
को शायद अक्षमता और सक्षमता में
भेद नहीं मालूम है।
दिल्ली में आज तक कभी
जिला, ब्लाक, विश्वविद्यालय और
कालेज इकाई में
एनएसयूआई नहीं पहुंचा था।
हमने यह काम महज आठ
महीने में पूरा कर दिखाया था।

जहां तक केन्द्रीय कार्य समिति के फैसले का सवाल है, उसकी कोई बैठक दिल्ली के मामले को लेकर हुई ही नहीं, ऐसा असंतुष्ट गुट के एक नेता का दावा है। उनके अनुसार जिस समय यह बैठक होने की बात कही जा रही है, उस समय १६ में से मात्र ३ पदाधिकारी ही राजधानी में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सर्वसम्मत फैसले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य इकाई भंग करने के बारे में जारी अधिकृत विज्ञप्ति तक में भी केन्द्रीय कार्यसमिति का जिक्र नहीं, बल्कि 'अध्यक्ष के आदेशानुसार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

इन परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं से और कुछ साफ हो या न हो, पर यह जरूर उजागर है कि सिद्धांतों की जगह व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस संघर्ष और रस्साकशी के पीछे विलय जितना बड़ा मुद्दा है, उतना ही बड़ा मुद्दा महत्वाकांक्षा, मनमुटाव और बड़े नेताओं की गुटबंदी का भी है। छात्र और खास कर दिल्ली आधारित राजनीति का अर्थ है अपने भावी राजनीतिक दायरे का विस्तार करना। इस बात से दोनों पक्ष बेखबर नहीं हैं। ध्यान रहे कि मनीष तिवारी और रमेश सब्बरवाल कुछ समय पूर्व तक संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर साथ-साथ काम कर रहे थे। आज इनमें से एक जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है, तो दूसरे के मन में कुछ क्षोभ या असंतोष का बीजारोपण होना अस्वाभाविक नहीं है। स्पर्धा विशेषकर इस मुद्दे को लेकर भी है कि दो वर्ष बाद अध्यक्ष पद से एक के रिटायर होने पर कदाचित दूसरा गद्दीनशीन हो सकता है। शायद इसी कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कद छोटा करना शुरू कर दिया था।

पद पर नजर: विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस दिशा में पहला कदम यह उठाया गया कि हर क्षेत्र में अध्यक्ष की दखलअंदाजी आरंभ हो गयी, भले ही वह मीटिंग बुलाने की बात हो या सदस्यता-अभियान के तहत दाखिला फार्म बांटने का मुद्दा जो विशेष कर पैसे संबंधी तू-तू मैं-मैं का कारण बन गया है। मनीष तिवारी का दावा है कि सदस्यता-अभियान के तहत दिल्ली राज्य इकाई को २० हजार फार्म दिये गये थे, उनमें से केवल एक हजार फार्म वापस हुए। शेष का आज तक पूरा हिसाब-किताब पूर्व अध्यक्ष सब्बरवाल ने नहीं दिया। इसके विपरीत सब्बरवाल का कहना है, "फार्म सीधे विभिन्न जिला इकाइयों को गत ५ फरवरी की बैठक के बाद बांटे गये थे। उक्त बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी उन्हें सीधे दिया गया था, मेरे जरिए नहीं। अत: उन्हें वापस लौटाने की जवाबदेही मेरी कैसे हुई?"

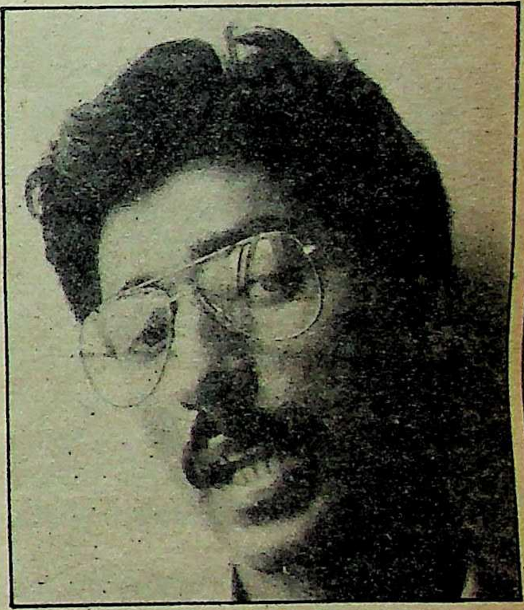
हमने काम किया, चमचागिरी नहीं: रमेश सब्बरवाल

इस आपसी वैर-वैमनस्य की धीमी-धीमी आग तब चिंगारी के रूप में भड़की, जब गत मार्च के

सब्बरवाल की उपेक्षा : पाक दूतावास के सामने प्रदर्शन

विपक्षी दलों द्वारा आयोजित भारत बंद के दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास दुकानें खुली रखने और रैली करने का निश्चय किया। चंडीगढ़ निवासी और राजधानी में अपेक्षाकृत प्रभावहीन मनीष तिवारी ने रैली में सब्बरवाल के सहयोग की अपेक्षा की। किंतु रैली स्थल पर पहुंचने पर उन्हें सब्बरवाल के असहयोगपूर्ण रुख का पता चला। कारण मुश्किल से २५ लोग थे। इस प्रकार प्रस्तावित रैली बुरी तरह विफल रही। तिवारी को यह असहयोग नागवार गुजरा।

जवाबी हमले का माकूल मौका तब हाथ लगा, जब पंजाब में पाकिस्तानी दखलअंदाजी के खिलाफ गत १८ अप्रैल को एनएसयूआई ने पाक दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यद्यपि सब्बरवाल ने इस मौके पर काफी तादाद में प्रदर्शनकारियों को एकजुट किया था, किंतु तिवारी ने उन्हें या उनके गुट के किसी व्यक्ति को उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया, जिसने दूतावास के अंदर जाकर ज्ञापन पेश किया।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ठीक उसी दिन एक और सनसनीखेज कांड हो गया, जिसने आग में घी का काम किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने आस्कर फर्नांडीस को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मनीष तिवारी के कमरे में गत ६ अप्रैल को अपने साथियों सहित कथित सेक्स कांड में संग्लन होने का ब्यौरा था। कदाचित तिवारी गुट के मन में यह आशंका जड़ जमा गयी कि यह सब्बरवाल के इशारे पर किया गया है। अत: उन्हें दंडित करने के लिए कोई कारगर कदम उठाना आवश्यक हो गया। दूसरे दिन ही तिवारी ने सब्बरवाल का इस्तीफा मांगा। सब्बरवाल यह कड़वा घूंट आसानी से पीने वाले नहीं थे। उन्होंने न केवल अपना, बल्कि समूचे राज्य इकाई के पदाधिकारियों का इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। ऐसी सूरत में तिवारी के सामने दिल्ली इकाई को भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उल्लेखनीय है कि आज तक न तो राज्य इकाइयों का पुनर्गठन हुआ है, न पदाधिकारियों का चयन।

आस्कर की भूमिका : इस समूचे प्रकरण में प्रभारी महासचिव आस्कर फर्नांडीस की भूमिका अस्पष्ट रही है। सब्बरवाल मानते हैं कि उन्हें राजनीति में लाने और बढ़ाने का श्रेय आस्कर का ही है। श्री आस्कर ने स्वयं 'माया' से बातचीत में स्वीकारा है कि सब्बरवाल वर्षों से संगठन की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी उनसे काम लिया जायेगा। अत: इस गाढ़े समय पर उन्होंने सब्बरवाल से मुंह क्यों मोड़ लिया? राज्य इकाई भंग करने से पूर्व मनीष तिवारी ने आस्कर की सहमति ली, इसमें संदेह है। कारण यह कि आस्कर प्रारंभ से सुलह-सफाई कराने पर जोर दे रहे थे। किंतु ऐसा लगता है कि मनीष तिवारी इसके पक्ष में नहीं थे। पानी सिर से गुजर जाने के बाद आस्कर के पास दो ही रास्ते बच रहे थे। एक मनीष तिवारी के खिलाफ आरोपों की जांच और कार्रवाई की जाये। दो, रमेश सब्बरवाल और उनके गुट को चले जाने दिया जाये। शायद दूसरे में ही उन्होंने संगठन और अपनी खैर समझी। ज्ञात रहे कि कुछ दिन पूर्व गुरुदास कामत के मामले में वह विवाद के बवंडर में फंस चुके थे। इसलिए एक दूसरे अग्रिम संगठन में पुन: ऐसी नौबत आना उनके लिए अधिक हानिकर होता। क्योंकि कांग्रेस में प्रभावशाली व्यक्ति की जड़ खोदने वालों की कमी नहीं है। नतीजतन सब्बरवाल और उनके गुट को बलि का बकरा बनना पड़ा।

दरअसल, रमेश सब्बरवाल जैसे लोग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के आपसी कलह में मोहरे बने हुए हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में एनएसयूआई की जंग बड़े नेताओं की भड़काई हुई है। कारण मनीष तिवारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने के पूर्व दिल्ली के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। इनमें एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, श्रीमती ताजदार बाबर आदि शामिल हैं। यही वजह है कि मामले ने दबने के बजाय तूल पकड़ा है।

प्रश्न यह है कि कांग्रेस के छात्र राजनीति में जड़ जमाने के शुरुआती अभियान पर इसका क्या असर पड़ेगा? छात्र राजनीति पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों के अनुसार कांग्रेस ने शायद उच्चशिक्षा संस्थानों में सक्रिय राजनीति करने का महत्व पहचान लिया है, जैसा कि वामपंथी पार्टियां अब तक करती आयी हैं। इस मसले पर आस्कर का कहना है, "यदि अन्य पार्टियां इसका लाभ उठाती हैं तो हम क्यों हाथ-पर-हाथ रख कर तमाशाई बने रहें?" शायद इसी जल्दबाजी में कांग्रेस आज कच्चा-पक्का सब कुछ बटोरने को उद्यत है। किंतु इस प्रयास में वह अपने ही घर में पड़ी दरार को जिस ढंग से नजरअंदाज कर रही है, वह अंततः घातक सिद्ध हो सकता है।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

विवाद दस्यु-संरक्षण का

बीएमपी के डीआईजी शिवचंद्र झा ने एक बार नये सिरे से रोहतास के राजनेताओं द्वारा दस्यु गिरोहों को संरक्षण दिये जाने के संवेदनशील पुराने मामले को छेड़ कर किस प्रकार की खलबली मचा दी है?

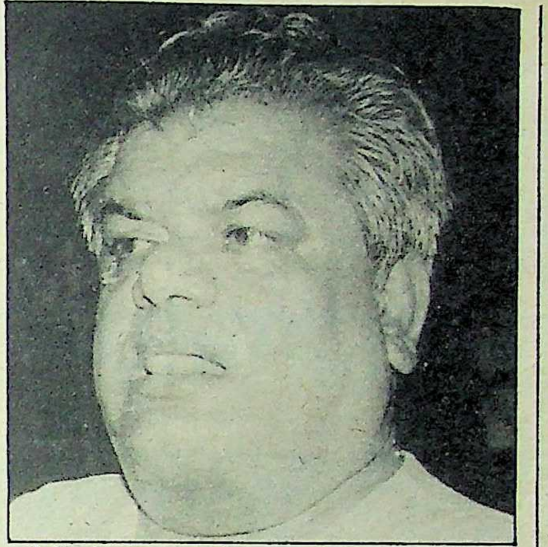

डकैतों को संरक्षण नहीं : सहकारिता कुबेर सांसद तपेश्वर सिंह

विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख खंड १५०० फुट ऊंचा कैमूर पहाड़ जो पिछले एक-डेढ़ दशक से दस्यु-आतंक का केंद्र रहा है, अचानक हाल में राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है।

इस विवाद का मंगलाचरण तब हुआ, जब विगत १८ मई को बीएमपी के डीआईजी शिवचंद्र झा ने रोहतास की यात्रा के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक जेएम कुरैशी सहित कुछ अन्य आला पुलिस अधिकारियों को बेतार से एक गुप्त संदेश दिया कि कैमूर के कई कुख्यात डाकुओं— मसलन, बबन मिश्र, रामवचन यादव और धमड़ी खरवार आदि के गिरोहों को विक्रमगंज के इंका सांसद कुबेर तपेश्वर सिंह, इंका के विधान पार्षद रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश नारायण मिश्र, सासाराम से लोकदल विधायक रामसेवक सिंह व चेनारी सुरक्षित क्षेत्र से लोकदल विधायक छेदी पासवान द्वारा संरक्षण देने के कई ठोस प्रमाण मिले हैं। बीएमपी के डीआईजी ने अपने बेतार संदेश में इन सांसदों व विधायकों की गिरफ्तारी की भी इल्तिजा की।

यों, राजनेताओं द्वारा दस्यु-गिरोहों को संरक्षण देने की बात आज से कई वर्ष पूर्व चर्चित पुलिस अधिकारी डीएन गौतम ने भी एक बार जोरदार ढंग से तब उठायी थी, जब वह रोहतास में आरक्षी अधीक्षक के रूप में तैनात थे। कहते हैं कि गौतम ने सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में गिरीश मिश्र व तपेश्वर सिंह का नाम उस समय भी लिया था। पर गौतम की वह रिपोर्ट तो ठंडे बस्ते में पड़ी ही रह गयी, साथ ही इन्हीं सब मामलों को उठाने के कारण गौतम का रोहतास से तबादला भी कर दिया गया। पर अभी जबकि बीएमपी के डीआईजी ने फिर उस सोये हुए मामले को छेड़ दिया है, तो जाहिर है कि राजनीतिक हलके में खलबली मची हुई है। सांसद तपेश्वर सिंह ने इस आरोप का खंडन करते हुए पुलिस महानिदेशक से पूरे मामले की जांच की मांग की और कहा कि अगर कैमूर के दस्युओं को संरक्षण देने का आरोप उन पर साबित हो जाता है, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। दूसरी तरफ इंका विधान पार्षद गिरीश मिश्र 'माया' से कहते हैं, "डीआईजी ने नितांत गैरजिम्मेदाराना काम किया है। यह मेरी छवि को बरबाद करने का कुचक्र है।" 'माया' से एक अनौपचारिक भेंट में गिरीश मिश्र ने कहा, "लगता है इस डीआईजी को गौतम ने कुछ ब्रीफ किया है। इस तरह का गलत आरोप लगाने के पूर्व उन्हें प्रमाण जुटाना चाहिए था। अगर उनके पास कोई प्रमाण है, तो वह पेश करें। अगर वह प्रमाण पेश नहीं कर पाते, तो उन्हें सेवामुक्त किया जाये।" दूसरी तरफ डीआईजी बीएमपी अपनी सरकारी नौकरी की सीमा के कारण पूरे विवाद पर कुछ भी मुंह नहीं खोलना चाहते। इधर गुजरे वर्षों में कैमूर से पूरे रोहतास पर हुकूमत करनेवाले चर्चित दस्यु सरदारों मोहन बिंद, धर्मदेव खरवार, मिश्री खरवार, दादा व हाकिम आदि का अंत हुआ, तो कई नये गिरोह उभर कर सामने आये। पर इतना जरूर है कि पहले की तरह का आतंक कैमूर में अब नहीं है, क्योंकि जो नवोदित दस्यु सरदार हैं भी, वे फिलहाल जेल की सींखचों के पीछे हैं।

कैमूर रेंज में पदस्थापित आरक्षी उपाधीक्षक ए इंदवार 'माया' से कहते हैं, "कैमूर के सभी दस्यु गिरोहों के सरदार तो अभी जेल में दिन गुजार रहे हैं। रामवचन यादव अभी बक्सर जेल में बंद है, इसलिए उसका गिरोह लगभग टूट चुका है। धमड़ी खरवार के गिरोह की भी वही स्थिति है। धमड़ी अभी अपने साथियों सहित मिर्जापुर जेल में कैद है। अभी बबन मिश्र और बिलेटन चमार का गिरोह जरूर सक्रिय है। ये दोनों दस्यु छांगुर गिरोह में थे।"

कैमूर के गिरोहों पर काबू पाने के लिए आरक्षी उपाधीक्षक इंदवार ने अपने साथ खास तौर से दो सिपाहियों रामगहन यादव और नथुनी यादव को रखा हुआ है। कैमूर के पास ही स्थित सड़की गांव के निवासी रामगहन ने मशहूर दस्यु सरदार मोहन बिंद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मोहन की हत्या के एवज में रामगहन को इनाम के रुपए तो मिले ही, साथ-साथ पुलिस में सिपाही की भी नौकरी मिल गयी। इसी तरह नथुनी यादव ने कैमूर के कुख्यात दस्यु धर्मदेव खरवार के प्राण लिये थे। नतीजतन, नथुनी को भी पुरस्कार स्वरूप सिपाही की नौकरी मिली। धर्मदेव की हत्या करने के कारण धर्मदेव के उत्तराधिकारी धमड़ी खरवार ने नथुनी के मामा शिवाधार यादव की हत्या कर डाली और चैनपुर में रह रहे नथुनी के कुछ रिश्तेदारों को भी मार डाला। इसी प्रकार मोहन बिंद को मारने का खमियाजा रामगहन के फुफेरे भाई को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा।

दस्यु-विरोधी मुहिम : ए इंदवार

छवि बिगाड़ने का कुचक्र : गिरीश नारायण मिश्र

आरक्षी उपाधीक्षक इंदवार 'माया' से कहते हैं, "रामगहन व नथुनी चूंकि कैमूर के चप्पे-चप्पे से अवगत हैं, इसलिए इनका सदुपयोग दस्यु गिरोहों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।"

पुलिस अधिकारी शिवचंद्र झा बिहार के दिग्गज राजनेताओं पर चोट करने के लिए चर्चित रहे हैं। जहानाबाद जिले के अरवल-नरसंहार के समय झा बिहार सरकार के खुफिया विभाग में पदस्थापित थे। झा ने उस समय भी अपने खुफिया प्रतिवेदन में अरवल कांड के सिलसिले में बिहार के पूर्व काबीना मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह का नाम लेकर राजनीतिक हलकों में कंपन ला दिया था। इसी कारण से उस समय झा को विभागीय प्रोन्नति पाने में भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इस समय जबकि फिर तपेश्वर सिंह जैसे नेताओं को झा ने आड़े हाथों लिया है, तो पता नहीं उन्हें इस दुस्साहस का कैसा दंड भुगतना पड़े?

कैमूर पहाड़ी खामोश है। वहां के सघन जंगल में विकास से कोसों दूर जिंदगी जी रहे आदिवासी व अन्य अपनी स्थायी व्यथा में 'खुशहाल' हैं, पर बिहार राजनीति के धनी खिलाड़ियों को कैमूर ने बेशक तड़पा रखा है।

—विकास कुमार झा

छाया : प्रभाकर

मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद

विधानसभाध्यक्ष और मुख्यमंत्री आमने-सामने

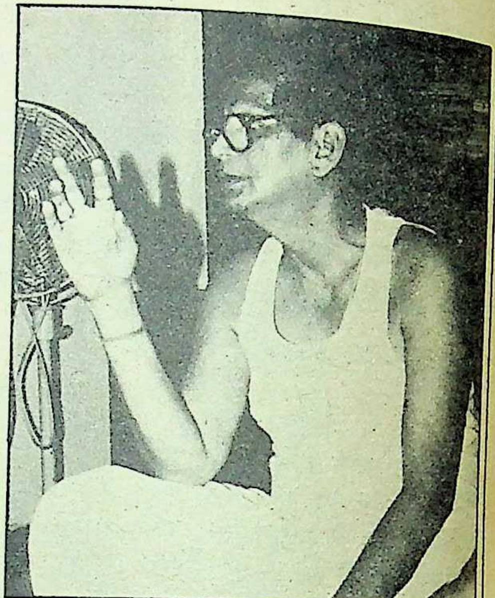

अध्यक्ष शिवचंद्र झा

बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा और विधानसभाध्यक्ष शिवचंद्र झा के बीच हाल में काफी उग्र हुए कलह की जड़ें तीस साल पुरानी हैं। दोनों झाओं के बीच १६ मई से शुरू हुए नये युद्ध को शांत करने के लिए यद्यपि मई के अंतिम सप्ताह में प्रयास हुए हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच स्थायी संधि संभव है?

मैथिली में एक चोटी के व्यंग्यकार थे स्व० हरिमोहन झा। अपनी एक प्रसिद्ध व्यंग्य कथा में उन्होंने एक जगह लिखा है कि जीवन में उन्होंने कभी दो झाओं को एक साथ नहीं देखा। दो झाओं को उन्होंने सिर्फ एक ही जगह एक संग देखा था—झाझा स्टेशन पर। मैथिली के उन स्वर्गीय व्यंग्यकार महाशय की यह उक्ति इन दिनों बिहार राजनीति में भी सौ फीसदी चरितार्थ हो रही है, जबकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष शिवचन्द्र झा मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के विरुद्ध खुलकर मुहिम छेड़े हुए हैं।

१६ मई को शिवचंद्र झा ने पटना स्थित सभी अखबार के दफ्तरों में अपने परिचित पत्रकारों को अचानक यह सूचना भिजवायी कि वे तत्काल प्रेसवालों से मुलाकात की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ठीक एक दिन पूर्व वह शिमला से लौटकर आये ही थे। थोड़ी ही देर में विधानसभा स्थित अध्यक्ष के कक्ष में पत्रकार आ जुटे। संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि उनके भाई स्व० राधाकृष्ण झा, जिनकी हत्या उनके गांव नीमागढ़ में १६ अक्तूबर, १६८१ को कर दी गयी थी, के हत्यारों का फिर उनके खिलाफ मनोबल बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा, उनकी जान व उनके परिजनों का जीवन हर पल खतरे में है। अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि कुछ 'बड़ी हस्तियों' ने नीमागढ़ के हरिजनों को पटना लाकर उनके विरुद्ध धरने पर भी बिठाया।

शिवचंद्र झा अभी पत्रकारों को संबोधित कर ही रहे थे कि अचानक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में आलमनगर क्षेत्र के लोकदल विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने प्रवेश किया। वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को एक टेप सुनाने की पेशकश की, जिसमें शिवचंद्र झा के गांव नीमागढ़ के एक हरिजन जीवलाल दास का बयान टेप था। जीवलाल दास के उस संक्षिप्त बयान में कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ धरना देने के लिए मुख्यमंत्री के साले बच्चा झा उन लोगों को तैयार कर के पटना लाये थे।

विवादास्पद टेप : शिवचंद्र झा के संवाददाता सम्मेलन में अचानक टेप सहित अवतरित हुए विपक्षी विधायक वीरेंद्र सिंह से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या १० मई को विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पटना में धरना देने आये हरिजन जीवलाल दास से टेप पर यह इंटरव्यू खुद उन्होंने लिया, तो वीरेन्द्र सिंह ने इससे इनकार करते हुए कहा कि खुद उन्होंने तो नहीं, पर उनके एक विश्वसनीय कार्यकर्ता ने जीवलाल से बातचीत को टेप किया, जिसका नाम वह अभी नहीं बतायेंगे। बहरहाल, विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में जमा पत्रकार वीरेंद्र सिंह से बहस कर रहे थे और वीरेंद्र लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि टेप की प्रामाणिकता का जिम्मा उन पर है। शिवचंद्र झा ने भी पत्रकारों से कहा कि जीवलाल दास की आवाज से वह परिचित हैं और यह टेप गलत नहीं है।

अपने संवाददाता सम्मेलन में शिवचंद्र झा ने विधानसभा के बरखास्त अवर सचिव अरविंद सिंह का भी उल्लेख किया और कहा कि बिंदेश्वरी दुबे को हटाकर जब बिहार में नये मुख्यमंत्री की चर्चा जोरों पर थी, उस समय भी उनके खिलाफ अरविंद सिंह को कुछ लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। प्रकारांतर से शिवचंद्र झा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे।

बहरहाल, शिवचंद्र झा की प्रेस कांफ्रेंस से जब अखबारों के प्रतिनिधि लौटे, तो शाम होते-होते पटना का राजनीतिक माहौल गर्म था। सभी पत्रकार इस गर्म खबर को सुर्खियों के साथ बनाने ही जा रहे थे कि बिहार इंका अध्यक्ष तारिक अनवर का एक अप्रत्याशित बयान अखबारों में पहुंचा, जिसमें शिवचंद्र झा को आड़े हाथों लिया गया था। तारिक अनवर ने अपने बयान में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस तरह की प्रेस कांफ्रेंस करना खेदपूर्ण है। कायदे की बात यह होती कि वह अपनी बात पहले दल के भीतर उठाते। इसके लिए प्रेस में जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। तारिक अनवर के बयान में मुख्यमंत्री आजाद को संकेत कर कहे गये इस अंश से पत्रकार भी चकित थे, जिसमें कहा था कि सुदीर्घ राजनीतिक जीवनकाल दल के एक सम्मानित वरिष्ठ नेता पर इस तरह का आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तारिक अनवर ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति प्रकट की कि विधानसभा

अध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस में लोकदल के एक विधायक को टेप सुनाने की अनुमति दी गयी। तारिक अनवर के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में विस्मय स्वाभाविक था, क्योंकि अब तक यही धारणा सभी के मन में कायम थी कि तारिक अनवर मुख्यमंत्री आजाद के खिलाफ हैं। पर जिस तरह फौरी ढंग से तारिक अनवर मुख्यमंत्री की तरफदारी में आये, उसने यह साफ कर दिया कि वह पूरी तरह मुख्यमंत्री के साथ हैं, वरना शिवचंद्र झा ने जब प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री पर परोक्ष चोट की, तो तारिक गद्‌गद ही होते। मुख्यमंत्री के पक्ष में बयान की बात तो दूर थी। खुद शिवचंद्र झा के लिए भी यह बात चौंकानेवाली थी, क्योंकि वह तारिक से अपने ऊपर इस तरह हमले की उम्मीद नहीं करते थे। परोक्ष रूप से तारिक ने उन्हें अनुशासन का सबक दिया था।

बयानबाजी का दौर: इस सबके बाद लोकदल विधायक वीरेंद्र सिंह ने तारिक अनवर के बयान के विरुद्ध एक बयान जारी कर जब यह कहा कि तारिक अनवर का इस विवाद में यह वक्तव्य देना अनुचित है, तो तारिक समझ गये कि वीरेंद्र सिंह का यह बयान कहां से प्रेरित है। इसी बीच जनता पार्टी विधायक दल के नेता रघुनाथ झा व हायाघाट के विधायक व सीपीएमएल के नेता उमाधर सिंह ने शिवचंद्र झा की तरफदारी की शैली में बयान जारी किया। तभी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष व सकरा क्षेत्र के लोकदल विधायक शिवनंदन पासवान के तीखे बयान ने शिवचंद्र झा की तरफदारी में विपक्षी विधायकों की सक्रिय भूमिका पर तत्काल रोक लगा दी। शिवनंदन पासवान ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि जिस आदमी ने स्व० कर्पूरी ठाकुर को सदमा पहुंचा कर उनकी मौत के लिए परिस्थिति कायम कर दी, उस आदमी (शिवचंद्र झा) को मारने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? शिवनंदन ने कहा, "स्व० कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से जिस अलोकतांत्रिक तरीके से शिवचंद्र झा ने हटाया था, वह शुद्ध रूप से लोकतंत्र की गरिमा व संविधान के खिलाफ था।" शिवनंदन पासवान के इस बयान ने विपक्षी विधायकों को धर्मसंकट में ला खड़ा किया और उन्होंने कदम पीछे हटा लिये।

इस पूरे कांड में विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस में नीमागढ़ के हरिजन जीवलाल दास का टेप सुनाने के लिए चर्चित लोकदल विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह 'माया' से कहते हैं, "शिवचंद्र झा छात्रजीवन में भागलपुर में मेरे सहपाठी थे। वह मुझसे एक वर्ष सीनियर थे। उन्हीं दिनों से उनसे मेरी अंतरंगता रही है। शिवचंद्र झा का मुख्यमंत्री से जो तनाव है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं। मैंने जब देखा कि शिवचंद्र झा के गांव के हरिजनों को पटना में धरने पर बिठाकर विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, तभी मैंने अपना एक आदमी भेजकर बेलीरोड पर धरने पर बैठे हरिजनों में से एक जीवलाल दास का बयान टेप करवाया, जिसमें उसने कहा कि मुख्यमंत्री के साले बच्चा झा ने उन लोगों को अध्यक्ष के खिलाफ भड़काया। विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं माना जाता, इसलिए उनकी प्रेस कांफ्रेंस में मेरे द्वारा टेप बजाये जाने को गलत रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बिहार इंका अध्यक्ष तारिक अनवर के बयान पर मुझे आपत्ति है।"

करो
जुल्म के विरोध में

विवाद का ताजा मुद्दा : पटना में हरिजनों का विधान सभा अध्यक्ष के विरुद्ध धरना

आखिर १० मई को पटना में अपने गांव नीमागढ़ के अट्ठारह हरिजनों द्वारा दिये गये धरने को लेकर शिवचंद्र झा इस तरह क्यों उखड़ गये, इसे जानने के लिए आज से सात साल पीछे लौटना होगा। भागलपुर जिले के बेलहर थाने के तहत एक गांव है, राजपुर-जो ब्राह्मणबहुल बस्ती है। राजपुर से तकरीबन ५०० गज की दूरी पर ८० वर्ष पूर्व शिवचंद्र झा के पूर्वज नीमागढ़ में जा बसे। शिवचंद्र झा के परिवार के पास बहुत जमीन थी, सो उस पर काम करने के लिए मजदूरों को हर पल सुलभ रखने के लिए शिवचंद्र के परिजनों ने नीमागढ़ में अपनी जमीन पर हरिजनों को बसाया। १९ अक्तूबर, १९८१ को शिवचंद्र झा के बड़े भाई राधाकृष्ण झा की हत्या हो गयी। यह शक नीमागढ़ के हरिजनों पर ही गया। राधाकृष्ण झा की हत्या के ठीक अगले दिन यानी २० अक्तूबर, १९८१ को नीमागढ़ के एक हरिजन मन्नूदास की भी हत्या हो गयी। हत्या के दोनों मामलों में पुलिस केस हुआ। स्व० राधाकृष्ण झा की हत्या के मामले में नीमागढ़ के हरिजनों पर मामला अभी भी चल रहा है। सात साल तक अदालत में पिसने के बाद १० मई को नीमागढ़ के हरिजन लगभग सतरह-अट्ठारह की तादाद में पटना के बेली रोड वाले मामले की वापसी के लिए धरना देने पहुंचे। शिवचंद्र झा उस समय शिमला के दौरे पर थे। १५ मई की शाम यात्रा से पटना लौटे, तो पटना के सभी प्रमुख अंग्रेजी-हिंदी के दैनिकों में अपने खिलाफ धरने पर बैठे नीमागढ़ के हरिजनों का चित्र देख वह सख्त नाराज हुए और उन्हें इसमें मुख्यमंत्री का हाथ नजर आया, तो १६ मई को उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस बुला ली।

खंडन: दूसरी तरफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हरिजन सेल के अध्यक्ष ओमप्रकाश पासवान अपने पदाधिकारियों के संग नीमागढ़ गये और उस जीवलाल दास का एक और बयान टेप पर लिया, जिसका बयान वीरेंद्र सिंह ने विधान सभा अध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस में सुनाया था। जीवलाल दास ने ओमप्रकाश को टेप पर कहा, "उससे टेप पर जबरन एक व्यक्ति ने पटना में बयान लिया। मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार उन लोगों को पटना नहीं ले गया। वह मुख्यमंत्री के साले बच्चा झा को जानता तक नहीं।" पटना लौटकर ओमप्रकाश पासवान ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर जीवलाल दास का टेप पर लिया बयान पत्रकारों को सुनाया। जवाबी हमले में ओमप्रकाश के खिलाफ उसी दिन अखबारों में ओमप्रकाश के हरिजन सेल को अवैधानिक बताया गया। ओमप्रकाश पासवान ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के अलावा पत्र लिखकर शिवचंद्र झा को भी आमंत्रित किया था कि नीमागढ़ के मामले में हरिजनों को गुमराह किया गया है।

अपनी सफायी में: क्या सचमुच मुख्यमंत्री के साले बच्चा झा ने नीमागढ़ के हरिजनों को पटना लाने का इंतजाम किया था? इसकी बाबत बच्चा झा 'माया' से कहते हैं, "अगर यह आरोप साबित हो जाये, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाये। शिवेन्द्रजी के प्रति मेरे मन में पूरा आदर है और मैं अकसर उनसे मिलता भी हूं। उनके इस आरोप पर मुझे आश्चर्य है।" इस पूरी राजनीतिक गरमाहट पर विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा 'माया' से कहते हैं, "सुनियोजित रूप से मेरे गांव के हरिजनों को मेरे विरुद्ध धरने पर बैठा कर मुझे हरिजन विरोधी करार देने की साजिश कुछ खास लोगों द्वारा की गयी। जहां तक मेरी प्रेस कांफ्रेंस में विधायक वीरेंद्र सिंह द्वारा टेप सुनाने की बात को इतना तूल दिया जा रहा है, वह गलत है। वीरेंद्र सिंह के पास प्रमाण था, उन्होंने सुनाया।" इस पूरी गहमागहमी पर

मुख्यमंत्री आजाद ने अबतक स्वयं कोई टिप्पणी नहीं की है।

वीरेंद्र सिंह

विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में जमा पत्रकार वीरेंद्र सिंह से बहस कर रहे थे और वीरेंद्र लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि टेप की प्रमाणिकता का जिम्मा उन पर है।

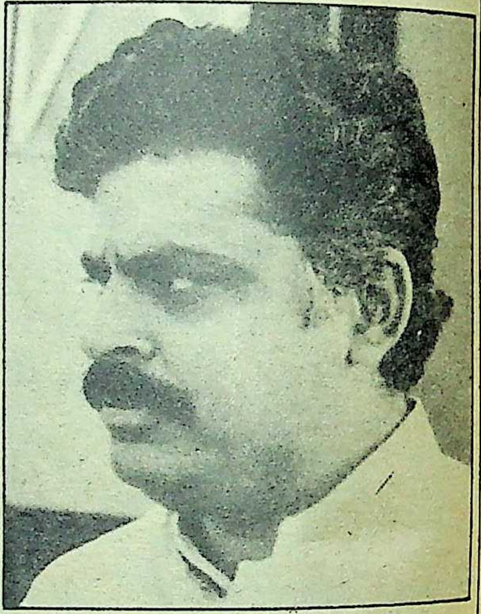

तारिक अनवर

तारिक अनवर ने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की कि विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस में लोकदल के एक विधायक को टेप सुनाने की अनुमति दी गयी।

पुरानी खुंदक: एक ही जिले भागलपुर में राजनीति करनेवाले मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद व विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा में आखिर तनाव कब से और क्यों है? इसे जानने के लिए कई वर्ष पीछे लौटना होगा। भागवत झा आजाद उम्र व राजनीति दोनों में शिवचंद्र झा से वरिष्ठ रहे हैं। १९६२ में भागवत झा आजाद को भागलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय शिवचंद्र झा पड़ोसी संसदीय क्षेत्र बांका से कांग्रेस टिकट के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे थे। पर नेहरू परिवार से चूंकि आजाद निकट थे और श्रीमती गांधी के राजनीतिक सचिव भी रह चुके थे, इसलिए आजाद भागलपुर से कांग्रेस टिकट पा गये। फिर भागलपुर से चूंकि मैथिल ब्राह्मण आजाद को कांग्रेस टिकट दिया गया था, इसलिए पड़ोसी संसदीय क्षेत्र बांका से एक दूसरे मैथिल ब्राह्मण शिवचंद्र झा को कांग्रेस टिकट दिया जाना नामुमकिन था। शिवचंद्र झा को इस बात का झटका लगा कि आजाद को अगर भागलपुर से टिकट नहीं मिलता, तो बांका से उन्हें अवश्य टिकट मिल जाता। इस बीच शिवचंद्र झा विधानसभायी क्षेत्र से भी टिकट पाने की कोशिश करते रहे, पर विफल रहे और उन्हें लगातार यह लगता रहा कि उनके राजनीतिक उदय में आजाद ही बाधक बन रहे हैं। आखिरकार संसद व विधानसभा का मोह शिवचंद्र झा को त्यागना पड़ा और १९६८ में विधान परिषद के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वह खड़े हुए। शिक्षक क्षेत्र से वह दो बार विधान पार्षद तो रहे, पर बार-बार उन्हें यह बात सालती रही कि वह संसद व विधानसभा में नहीं आ सके। १९७१ व १९७७ में फिर शिवचंद्र ने बांका संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पाने की विफल कोशिश की। आखिरकार १९८० में भागलपुर विधानसभायी क्षेत्र से उन्हें टिकट मिला। इस बार आजाद ने शिवचंद्र झा के टिकट का विरोध नहीं किया। आजाद भागलपुर से सांसद थे, अगर वह शिवचंद्र झा को भागलपुर से टिकट न देने के सवाल पर अडिग हो जाते, तो शिवचंद्र झा को टिकट मिलना शायद मुश्किल हो जाता। १९८५ में भी शिवचंद्र भागलपुर से विधायक हुए। पर आजाद से बजाय संबंध सुधरने के शिवचंद्र झा के संबंध बिगड़ते ही गये। इधर बिंदेश्वरी दुबे की जब मुख्यमंत्री-पद से छुट्टी किये जाने की चर्चा तेज हुई, तो शिवचंद्र झा भी मुख्यमंत्री-पद के प्रत्याशी बन गये। दिल्ली में उनके नाम को माखनलाल फोतेदार व सीताराम केसरी ने चलाया था। पर राजीव गांधी के पास जब फोतेदार ने शिवचंद्र झा का नाम चलाया, तो प्रधानमंत्री ने बस यह संक्षिप्त टिप्पणी कर फोतेदार के सभी तर्कों को खारिज कर दिया कि 'फोतेदारजी, आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं।' इस बीच शिवचंद्र झा बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से कर्पूरी ठाकुर को हटाकर विवाद के घेरे में थे, इसलिए भी मुख्यमंत्री-पद हेतु उनका दावा बेहद कमजोर पड़ गया था। हालांकि स्व० कर्पूरी ठाकुर के साथ यह सलूक उन्होंने इस सोच के तहत किया था कि इससे इंका आलाकमान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त होगा। पर शिवचंद्र झा का यह राजनीतिक गणित गलत था। १३ फरवरी की रात के ग्यारह बजे तक शिवचंद्र झा पूरी उम्मीद लगाये बैठे रहे कि उनका नाम मुख्यमंत्री-पद हेतु तय है। पर जब टेलीप्रिंटर पर उनके राजनीतिक दुश्मन भागवत झा का नाम बिहार के मुख्यमंत्री-पद हेतु आ गया, तो शिवचंद्र झा के लिए यह दोहरा झटका था। क्योंकि एक सदमा तो उन्हें खुद के न होने का लगा और दूसरा सदमा भागवत झा आजाद के होने से लगा। उन्हें लगा कि अब उनकी राजनीति पर ग्रहण लग जायेगा। हालांकि १४ फरवरी की सुबह मुख्यमंत्री-पद की शपथ लेने के बाद आजाद ने पहला काम किया शिवचंद्र झा के घर पर जाकर मिलने का। पर शिवचंद्र झा का जख्म इस सबसे भरा नहीं उलटे और हरा ही हुआ। राजनीतिक हलकों में स्वतः यह माना जाने लगा कि विक्षुब्ध राजनीति की डोर अब शिवचंद्र झा संभालेंगे। मुख्यमंत्री आजाद इस मामले में भाग्य के धनी हैं कि डा० जगन्नाथ मिश्र जैसे स्थायी विक्षुब्ध नेता के बजाय शिवचंद्र झा ने विक्षुब्ध राजनीति का मोर्चा खोला, जिनके पास उतना जनाधार नहीं। डा० जगन्नाथ मिश्र की तरह शिवचंद्र झा खुलेआम मारक राजनीति करने में भी प्रवीण नहीं हैं। हालांकि भागलपुर की राजनीति में कहलगांव के चर्चित निर्दलीय विधायक सदानंद सिंह से उन्होंने राजनीतिक समीकरण बिठाया है और बिहार के २० निर्दलीय विधायकों को सदानंद के माध्यम से एक जुट कर विधानसभा में 'बिहार कांग्रेस' के ग्रुप के रूप में २९ अप्रैल को मान्यता भी दी। सदानंद सिंह भागलपुर के कुख्यात अपराधी स्व० सुदामा मंडल को संरक्षण देने के लिए डा० जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में विवादास्पद हुए थे, जब डा० मिश्र के मंत्रिमंडल में वह राज्य मंत्री थे। इसी कारण सदानंद का कांग्रेस से टिकट भी कटा और कहलगांव से वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े। डा० जगन्नाथ मिश्र से भी शिवचंद्र झा की लगातार ठनी रही है। डा० मिश्र के कार्यकाल में शिवचंद्र विक्षुब्धों की जमात में थे। गत वर्ष जब डा० जगन्नाथ मिश्र ने शिवचंद्र झा के क्षेत्र में जाकर जनजागरण सभा की, तो नाराज शिवचंद्र झा ने बदले में डा० जगन्नाथ मिश्र के चुनाव क्षेत्र झंझारपुर की पद यात्रा कर डाली थी। इसलिए अभी जबकि शिवचंद्र झा मुख्यमंत्री से मोर्चा लेने की वर्जिश कर रहे हैं, तो डा० जगन्नाथ मिश्र उनकी मदद में नहीं आ रहे। स्व० चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवचंद्र झा कुछ दिनों के लिए काबीना मंत्री रहे और दुबे राज में विधानसभाध्यक्ष हुए। पर अब हाल की स्थितियों से ऐसा संकेत मिलता है कि डा० जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस किस्म का बनवास उन्हें भोगना पड़ा था, शायद वैसा ही बनवास कहीं उन्हें फिर न भोगना पड़े।

—विकास कुमार झा

छाया: प्रभाकर/ दीपक कुमार

पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा

गृहमंत्री की कृपा, तो डर काहे का !

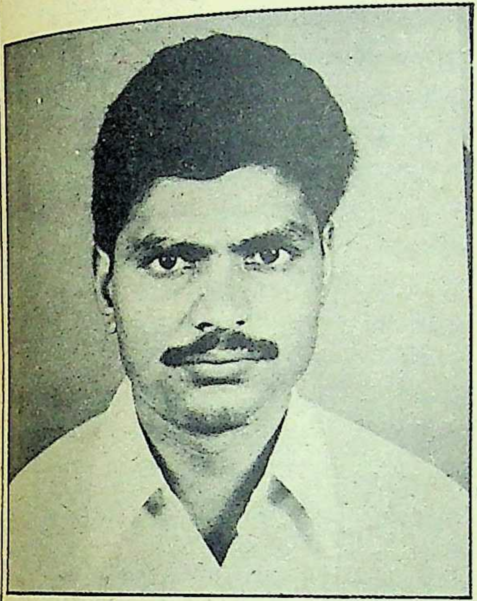

शराब का कथित व्यवसाय ? : कन्हैया लाल बैरवा

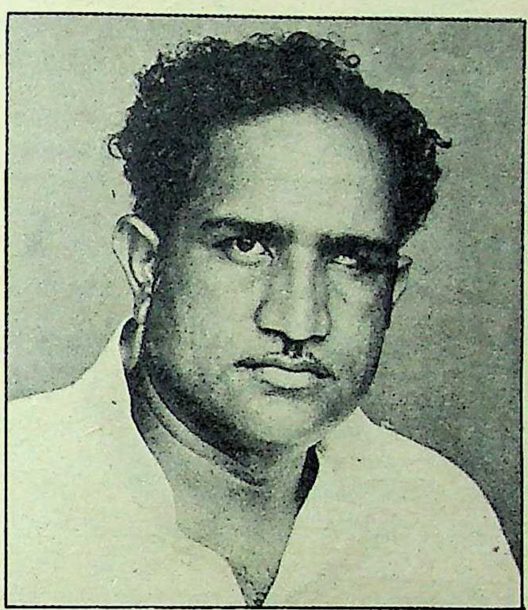

बैरवा के संरक्षक ? : पूर्वमंत्री दुल्हाराम, कांग्रेस-इ विधायक श्रीमती इकबाल कौर

राजनेताओं, पुलिस और असामाजिक तत्वों के गठजोड़ को जब राजनीति का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तो किस तरह का समाजघाती भ्रष्टाचार बेलगाम पनपने लगता है, इसका एक उदाहरण है, श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा का मामला। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से युक्त अनेक ज्ञापन मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भेजे गये, लेकिन आरोप है कि प्रभावशाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। होना तो यह चाहिए था कि राज्य सरकार बैरवा पर लगे सभी आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराती और यदि वह दोषी पाये जाते, तो उन्हें दंडित करती अन्यथा झूठा आरोप लगानेवाले दंडित होते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों ? :

राजस्थान के ६३,८२५ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले भी अब सरकार बदलने के साथ ही जात के आधार पर तय होने लगे हैं। पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया को अपने अफसर और कर्मचारियों में सबसे ज्यादा ईमानदार अगर जाट नजर आते हैं, तो केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिह को राजस्थान का सांसद होने के नाते अनुसूचित जाति के पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई बात पसन्द नहीं आती। केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिह के हितों के संरक्षक बने कांग्रेस-इ के पूर्वमंत्री दुल्हाराम, अनुसूचित जाति के अफसरों को प्रदेश में अपने सूबेदार नजर आते हैं। अगर किसी अफसर से दुल्हाराम खुश हों, तो फिर मुख्यमंत्री उसे नाराज करने का जोखिम उठाने से कतराते हैं। आरोप है कि सम्पन्न किसानों के जिले श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा को इसी कारण मुख्यमंत्री की भी छत्रछाया प्राप्त है। १ अगस्त, १९८६ से श्रीगंगानगर में पुलिस अधीक्षक का पद सम्भाले बैरवा पर श्रीगंगानगर जिला परिषद के प्रमुख चौधरी देवीलाल सहारण ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जिले की विधायक श्रीमती इकबाल कौर के पति विरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर शराब का व्यवसाय चला रखा है। सहारण के अनुसार श्रीमती कौर का परिवार अपराध जगत और अपराधियों से गहरी साठगांठ रखता है।

शराब के धंधे में आतंक का अपना स्थान है और यह आम चर्चा है कि इसे बनाये रखने में आनेवाली किसी भी अड़चन को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक बैरवा, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। सहारण के अनुसार, श्रीमती कौर के पति के गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिले के घूमड़वाली थाने के थानेदार को सबक सिखाने के लिए श्रीकरनपुर—पदमपुर बस मार्ग पर बस में यात्रा के दौरान बस रोककर उसके साथ मारपीट की गयी। उस थानेदार ने जब पदमपुर थाने में जाकर मारपीट करनेवालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही, तो पदमपुर के थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया।

हत्याएं : मुख्यमंत्री को दिये गये अपने ज्ञापन में सहारण ने जिले की मंडी पीलीबंगा में दो युवक ओम व तारू की १० अगस्त, १९८७, को की गयी हत्या के लिए श्रीमती कौर के पति के गिरोह को जिम्मेवार ठहराया है। उनका आरोप है कि पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाहों को डरा रहे हैं। सहारण ने इसी तरह हिरनावाली गांव में १५ सितम्बर, १९८७ में लाभसिह नामक व्यक्ति की हत्या के अपराधियों को जमानत पर भी रिहा करवाने के लिए ९० दिन तक चालान पेश नहीं करने की घटना का भी उल्लेख किया है। ९० दिन बाद जब चालान पेश किया गया,

तो अपराधियों ने अपनी जमानत करवा ली। इस अंतराल के एवज में ज्ञापन के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने दो लाख रुपए लिये।

इस जिले की हनुमानगढ़ ब्लाक कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष बलवंत सिह ने उक्त सारे आरोपों को दोहराते हुए ओम-तारू हत्याकांड के नामजद अपराधी पीटर उर्फ सुरेंद्रपाल सिह से ७० हजार रुपए रिश्वत लेकर उसे मुकदमे से निकालने का आरोप पुलिस अधीक्षक पर लगाया है। उनके अनुसार पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं सतर्कता ने जांच करने पर पाया था कि हत्याकांड से संबंधित थाने के थानेदार पृथ्वीसिह ने पुलिस अधीक्षक बैरवा के इशारे पर अपराधियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। थानेदार को इस जालसाजी के लिए विभागीय अनुशासन की धारा-१६ के तहत नोटिस देकर जांच करने व पुलिस लाइन श्रीगंगानगर में स्थानांतरित करने के आदेश महानिरीक्षक पुलिस ने जारी किये थे। इन आदेशों के बावजूद थानेदार इन पंक्तियों के लिखे जाने तक थाने में कार्यरत था।

शराब के धंधे में ? : कांग्रेस-इ विधायक केसी विश्नोई

शराब का व्यवसाय: जिला प्रमुख जहां पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा को श्रीमती कौर के पति के शराब व्यवसाय में १३ प्रतिशत का हिस्सेदार बताते हैं, वहीं बलवंत सिह प्रधानमंत्री को भेजे गये अपने ज्ञापन में हिस्से की रकम १३ लाख रुपएं बताते हैं। वह यह भी खुलासा करते हैं कि जिले के सूरतगढ़ तथा रायसिह नगर के शराब व्यापारियों के साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक केसी विश्नोई, कांग्रेस-इ विधायक श्रीमती इकबाल कौर तथा पूर्वकांग्रेस-इ विधायक राधेश्याम व सुनील विश्नोई भी शराब व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। आरोप है कि पुलिस अधीक्षक बैरवा जिले के २६ थानों से हर माह २ लाख, १३ हजार रुपए माहवारी के रूप में वसूल करते हैं। हर थाने में नियुक्ति का रेट तय है। मसलन, थाना अधिकारी बनने के लिए १५ हजार से ४० हजार रुपया तक देना होता है। हत्या के मामले की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को पांच हजार रुपए पुलिस अधीक्षक को देने होते हैं। अपराधी को हत्या के मुकदमे से निकालने के लिए एक या दो लाख रुपए देने होते हैं।

साक्षात्कार/लक्ष्मण सिंह,
गृहराज्यमंत्री

जांच के बगैर कुछ कहना ठीक नहीं होगा

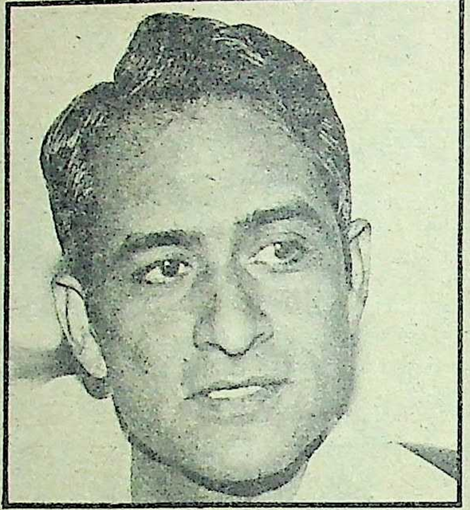

राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के विभागों के सहयोगी गृहराज्यमंत्री लक्ष्मण सिंह से 'माया' ने श्रीगंगानगर जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा से संबंधित ज्ञापनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। प्रस्तुत हैं, बातचीत के कुछ अंश:

माया: *कोई पुलिस अधीक्षक किसी व्यवसाय में हिस्सेदार होकर हत्या करने या हत्यारों को बचाने की चेष्टा करे, तो आप क्या कदम उठायेंगे?*

लक्ष्मण सिह: ऐसा पुलिस अधीक्षक या कोई भी पुलिस का कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी ऐसे अपराध में शामिल है, तो इसे निन्दनीय कहा जायेगा। अगर किसी के पास ऐसे तथ्य हैं, तो हमें प्रस्तुत करे। हम जांच कर उसे उसके अपराध की सजा निश्चित रूप से दिलवायेंगे।

माया: *श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख सहित आपके दल के स्थानीय नेताओं ने तथ्यों के साथ ज्ञापन दिया है, जिसमें बैरवा के भ्रष्टाचार के स्पष्ट उदाहरण हैं?*

लक्ष्मण सिह: मुझसे कुछ माह पूर्व जिला प्रमुख ने मौखिक रूप से पुलिस अधीक्षक के बारे में कुछ बातें कही थीं। तब हमने उनसे कहा था, ऐसे तथ्य मुझे दें। मेरे पास तो ऐसे तथ्य उन्होंने पेश नहीं किये। मुख्यमंत्रीजी गृह विभाग के स्वतंत्र जिम्मेदार हैं, उन्हें कोई ज्ञापन दिया हो और जांच के आदेश हुए हों, तो मुझे ज्ञात नहीं है। आप जानते हैं मैं तो उनका सहयोगी मंत्री हूं। बहरहाल, मैं ज्ञात करूंगा कि ऐसा कोई तथ्यों के साथ ज्ञापन गृह विभाग को मिला है क्या?

माया: *पुलिस महानिदेशक ने अप्रैल माह में पुलिस अधीक्षक बैरवा के खिलाफ राज्य सरकार से विभागीय जांच की सिफारिश की थी?*

लक्ष्मण सिह: अप्रैल माह में एसपी गंगानगर ने खिलाफ जांच करवाने के लिए? नाट टू माई नालेज, (मुझे ज्ञान नहीं है)

माया: *पुलिस अधीक्षक हत्या जैसे मामलों में राजीनामा करवाकर मामला रफा-दफा कर देते हैं, आप जानते हैं?*

लक्ष्मण सिह: आपकी बात किसी एक विशेष केस के संबंध में हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसे मामले में पुलिस अधीक्षक को राजीनामा करवाने की बात सोचना भी अपराध है। वैसे, श्रीगंगानगर सीमा प्रदेश होने की वजह से विशेष ध्यान की अपेक्षा रखता है। वहां के पुलिस अधीक्षक के संबंध में मौखिक शिकायतें तो मिली हैं, पर पुलिस अधिकारियों के संबंध में ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, जिन पर जांच के बगैर कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

माया: *आपके बयानों से ऐसा लगता है कि गृह विभाग के अधिकारी आपको घटनाओं और तथ्यों से अवगत नहीं कराते?*

लक्ष्मण सिह: मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मेरा स्वतंत्र विभाग नहीं है। सम्भवत: मुख्यमंत्रीजी के पास यह मामला आया हो। वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में वह स्वयं निर्णय करते हैं, गृहसचिव ने उन्हें तथ्यों से अवगत करा दिया होगा।

माया: *अगर आप निर्णायक होते, तो क्या करते?*

लक्ष्मण सिह: मैं मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तथ्यों की जांच कर गंभीरता से कार्रवाही होनी चाहिए।

—ओम सैनी

इनका आरोप है कि पुलिस अधीक्षक बैरवा पुलिस महानिदेशक के आदेश को भी नहीं मानते। बलवंत सिंह के अनुसार, जब पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के आदेशों की बात उन्हें कही जाती है, तो उनका जवाब होता है, "मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री और डीजीपी को डीजीपी बनानेवाले मेरे ही 'बोस' तो हैं।"

बलवंत सिंह ने अपने ज्ञापन में बैरवा के संरक्षक के रूप में बूटा सिंह का नाम लिखा है, पर बाद में उस पर काली स्याही फेरी है। बहरहाल, राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग के शराब के ठेकों का धंधा करनेवाले हनुमानगढ़ कस्बे के निवासी गंगाजल ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर कुछ और ही राज खोले हैं। वह बताते हैं कि इस वर्ष राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने जिला श्रीगंगानगर को तीन ग्रुपों में बांटकर निविदाएं मांगी थीं। इनमें कांग्रेस-इ विधायक श्रीमती इकबाल कौर के पति विरेन्द्र सिंह तथा देवर अरविन्दर सिंह के ग्रुप को सूरतगढ़ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसी ग्रुप को शराब के ठेके चलाने का टेंडर आवंटित हुआ, जिसमें हिस्सेदारी उन्हीं लोगों की है, जिनका उल्लेख जिला प्रमुख और हनुमानगढ़ ब्लाक कांग्रेस-इ कमेटी के अध्यक्ष करते हैं। इनका आरोप है कि अपना शराब का धंधा चलाने के लिए सूरतगढ़ ग्रुप ने तीन कत्ल किये हैं। दो कत्लों का उल्लेख जिला प्रमुख और ब्लाक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ के अध्यक्ष करते हैं, जबकि तीसरी हत्या हनुमानगढ़ कस्बे के सुभाष नामक युवक की हुई। पुलिस तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार कर लेती है। गंगाजल का कहना है, "संगरिया निर्वाचन क्षेत्र, जिला श्रीगंगानगर के विधायक केसी विश्नोई को जैसे ही इस हत्याकाण्ड का पता चला, उन्होंने जयपुर में बैठे पुलिस अधीक्षक बैरवा से हनुमानगढ़ पुलिस उप-अधीक्षक को फोन करवाया। फोन पर पुलिस उप-अधीक्षक से कहा गया कि हत्याकांड में गंगाजल ठेकेदार को फंसाओ," लेकिन पुलिस अधीक्षक के लिए जालसाजी करना मुश्किल था, क्योंकि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने अपराधियों को पकड़ा था। इसी संबंध में पुनः पुलिस अधीक्षक बैरवा ने अगले दिन विधायक श्रीमती इकबाल कौर के घर से लाइटनिंग काल किया, जिसका सबूत गंगाजल के पास उपलब्ध है। अब गंगाजल को डर है कि एसपी बैरवा उन्हें जिन्दा नहीं रहने देगा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री व पुलिस के आला अफसरों से अपनी रक्षा की दुहाई की है।

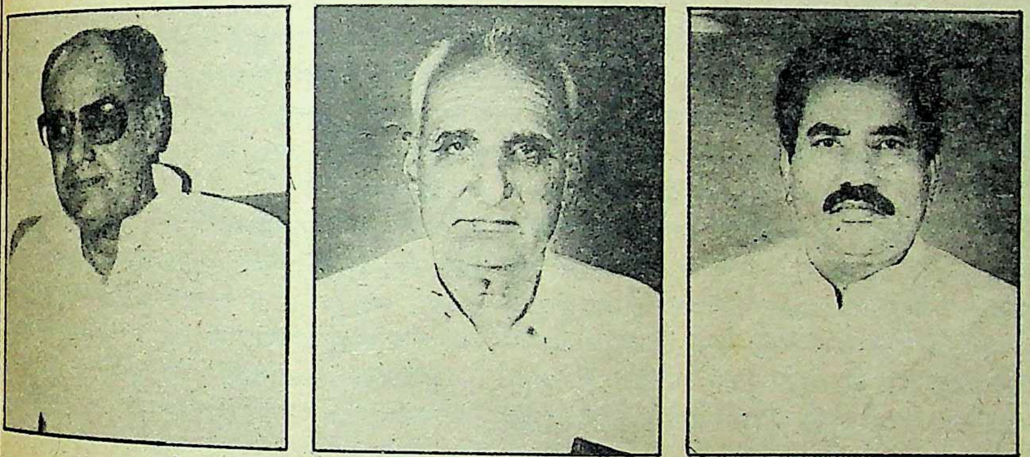

बैरवा पर गंभीर आरोप : देवीलाल साहरण, बलवंत सिंह, गंगाजल

कांस्टेबलों की भर्ती में रिश्वत : इधर पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया के पास पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने दिसंबर, १९८६ में ४५ कांस्टेबलों की भर्ती पैसे लेकर की। शिकायत में यह भी कहा गया था कि कुछ लोगों के आवेदन फार्म निर्धारित तिथि गुजर जाने के बाद लिये गये, और उनकी नियुक्ति की गयी। इसके अलावा यह भी शिकायत की गयी कि जिन लोगों के लिखित परीक्षा में कम अंक आये, उन्हें साक्षात्कार में अधिक अंक देकर उनका चयन कर लिया गया।

वैसे, पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने इस शिकायत पर अप्रैल, १९८८ में ही क्यों गौर किया, जबकि पूर्व गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत ने उक्त घपले की जांच पूर्व पुलिस महानिदेशक को आदेश दे, उप-महानिरीक्षक (सतर्कता) से करवा ली थी? निश्चित रूप से पहली जांच के पीछे मकसद बैरवा के तथाकथित 'बोसेज' को आतंकित करना था, वहां पिलानिया द्वारा गौर करने के पीछे तथ्यों की मजबूरी रही होगी।

बहरहाल, उप-महानिरीक्षक ने अपनी प्रारम्भिक जांच में पाया था कि भर्ती के लिए आवेदन फार्म कितने बेचे और कितने जमा हुए, इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया। यह तिथि भी दर्ज नहीं की गयी कि आवेदन फार्म कब प्राप्त हुए। इस जांच में यह भी उजागर हुआ कि बैरवा ने ज्यादातर चूरू जिले के लोगों को भर्ती किया, जहां वह पूर्व में पुलिस अधीक्षक थे। इसी तरह जहां सशस्त्र पुलिस में ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों को भर्ती किया गया, वहीं कांस्टेबलरी पुलिस में कम पढ़े-लिखे लोगों को, जबकि होना उलटा चाहिए था।

डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया को पुलिस अधीक्षक बैरवा के खिलाफ जांच के आदेश इसलिए भी राज्य सरकार से लेने पड़े, क्योंकि वह पुलिस अधीक्षक होने के साथ-साथ बैरवा न्यायाधीश का रोल भी अदा करने लगे हैं। ८ जुलाई, १९८६ को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में आवासन मंडल की जमीन पर कुछ लोगों ने झोंपड़ियां बनाकर कब्जा करना शुरू किया। इस जमीन पर वहीं के कोई प्रेम कटारिया, जनकलाल और केवल राम आंखें गड़ाये थे। झोंपड़ी बनानेवालों में कोई जगमाल और उसका भाई मणिराम प्रमुख थे। प्रेम कटारिया अपने साथियों के साथ जीप में झोंपड़ी बनानेवालों के बीच गया और झोंपड़ियां तोड़ने लगा। कहा-सुनी हुई, तो जनकलाल ने मणिराम को गोली से उड़ा दिया और भागने लगे। जगमाल और उसके साथियों ने कटारिया के साथ भागने वालों में से एक व्यक्ति हजारी को पकड़ लिया और पीट-पीटकर उसे जान से मार डाला। जगमाल इसके बाद थाने गया और दोनों हत्याओं की रिपोर्ट लिखायी। पुलिस ने जगमाल और उसके साथी सुरजाराम को तो हजारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, पर मणिराम की हत्या के आरोप में जनकलाल को नहीं पकड़ा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की तफतीश हनुमानगढ़ के पुलिस उप-अधीक्षक को सौंप दी। यहां जनकलाल की तरफ से यह तर्क पेश किया गया कि हत्या के दिन वह घटनास्थल पर था ही नहीं। दूसरी ओर आरोप है कि मृतक मणिराम के भाई जगमाल को यह बयान देने के लिए पुलिस अधीक्षक बैरवा ने मजबूर किया कि जनकलाल ने मणिराम की हत्या नहीं की। दोनों तरफ के इकबालिया बयान भारतीय दंड संडिता की धारा-१६४ में अदालत में कराये गये और हलफनामे लेकर पूरे मामले को समाप्त कर दिया गया। राज्य के पुलिस इतिहास में सम्भवतः यह पहला मामला था, जिसमें दो हत्याएं होने और मुजरिमों का पता होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये बिना हत्या के मामले में अपने स्तर पर फैसला कर दिया।

तत्कालीन गृहमंत्री ने इसकी जांच भी कराने के आदेश दिये थे। उप-महानिरीक्षक (सतर्कता) ने जांच की, तो पता चला कि पुलिस अधीक्षक बैरवा ने हत्या जैसे मामले में किसी निष्पक्ष आदमी की गवाही नहीं ली और मामले को रफा-दफा कर दिया। हत्या होने में कोई शक नहीं है, चूंकि लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट दर्ज हुई। अब पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने इन हत्याओं की जांच गुप्तचर (अपराध) पुलिस अधीक्षक से कराने के आदेश दिये हैं। बहरहाल, सारे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल बैरवा के रक्षक जिले के कांग्रेस-इ विधायक और पूर्वमंत्री दुल्हाराम नजर आते हैं और बताया जाता है कि पूर्वमुख्यमंत्री जोशी युवा कांग्रेस अध्यक्ष केसी विश्नोई एवं श्रीमती इकबाल कौर को अपने गुट में रखने के लिए बैरवा को बरदाश्त कर रहे थे, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह का ध्यान रखना पड़ रहा है।

—ओम सैनी

हरिदेव जोशी

गहलोत के खिलाफ जंग की शुरूआत

हरिदेव जोशी

अशोक गहलोत

चुप रहकर समाजवादी मंच के माध्यम से माथुर सरकार के खिलाफ चलायी मुहिम को अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिदेव जोशी ने मुखर हो कर अपना लिया है। उन्हें, अब साफ-साफ समझ में आने लगा है कि असली शत्रु कोई और नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अशोक गहलोत हैं। यही वजह है कि उन्होंने १६ मार्च व ५ अप्रैल, १६८८ को अपने समर्थक विधायकों से प्रधानमंत्री के पास अशोक गहलोत के तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला ज्ञापन भिजवाया। ५ अप्रैल वाले ज्ञापन में तो जोशी समर्थक विधायकों ने श्री गहलोत पर प्रदेश कांग्रेस संगठन को अपने पिट्ठुओं का अड्डा बनाने, दांडी मार्च के नाम पर कांग्रेस-इ की मजाक उड़वाने और अपने दबदबे से पैसा कमाने का आरोप लगाया था। ज्ञापन में कहा गया था कि जो अशोक गहलोत सांसद बनने से पूर्व मोटर साइकिल खरीदने के लिए बैंक से लिया ऋण वापस नहीं कर सका था, आज करोड़ों में खेल रहा है। हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्रित्व की अशोक गहलोत द्वारा की गयी मुखालफत को इस पत्र में पार्टी विरोधी करार देते हुए शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल को गहलोत के पिट्ठुओं का मंत्रिमंडल बताया गया था और प्रधानमंत्री से पार्टी हित में प्रदेश कांग्रेस संगठन में परिवर्तन करने की अपेक्षा की गयी थी।

बावजूद इस ज्ञापन के जब आलाकमान ने कोई कदम नहीं उठाया, तो असंतुष्टों ने प्रधानमंत्री के २ मई को जयपुर आने पर एक और प्रयास किया। इस बार मुलाकात न होने पर बिना हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भेजा गया, जिसमें पार्टी हित में अशोक गहलोत को कांग्रेस-इ से निकालने की मांग की गयी।

आलाकमान की इस चुप्पी और राजस्थान के असंतुष्टों को पसंद करनेवाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी को पद से हटाने के साथ ही जोशी बौखला गये। चतुर्वेदी को पद से हटाने का मतलब था, जोशी समर्थकों को यह समझाना कि प्रधानमंत्री की पसंद के संबंध में टीका-टिप्पणी बरदाश्त नहीं जायेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जोशी इस दौरान दल के सारे कार्यक्रमों में तथाकथित अनुशासित सिपाही की तरह हिस्सा लेते रहे। नाराज और खुश हर प्रादेशिक नेता से मिलने पर उनके चेहरे पर कांग्रेसी मुसकान चिपकी रही।

पर यह मुसकान ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। शिवचरण माथुर सरकार द्वारा जून माह में पंचायत चुनावों की घोषणा ने उन्हें कुछ कहने के लिए बेचैन कर दिया। इस बार जोशी ने आलाकमान के दफ्तर में फरियाद करने के बजाय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गहलोत से ही दो-दो हाथ करने की ठानी। १५ मई को उन्होंने अपने सात मित्रों के हस्ताक्षरोंवाला पत्र प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष के नाम जारी किया और प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष को भेजने से पहले प्रेस के लिए जारी कर दिया। पत्र में हस्ताक्षर करनेवालों में पूर्व मंत्री चन्दनमल वैद्य सांसद नवल किशोर शर्मा, सांसद विष्णु मोदी तथा जोशी मंत्रिमंडल के सदस्य मूलचन्द मीणा, दामोदर दास आचार्य और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हीरालाल देवपुरा शामिल थे। पांच साल पहले, हस्ताक्षर करनेवाली इस टीम का राजस्थान में काफी दबदबा था। प्रदेश कांग्रेस से संबंधित हर संगठन में इनके अनुयायी थे, पर आज इन बड़े नेताओं के पर कतरे जा चुके हैं।

बहरहाल, पत्र में पंचायत चुनावों की घोषणा करने को अच्छा बताते हुए आलोचना इस आधार पर की गयी कि यह राज्य सरकार का इकतरफा निर्णय है। पत्र में कहा गया है कि हर पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस के गरीब मतदाता, हरिजन, आदिवासी बड़ी तादात में आज राज्य से बाहर चले गये हैं। इस कारण चुनाव का यह समय अनुपयुक्त है।

पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के तालमेल पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है, "सत्ता और संगठन का यह तालमेल शायद आप और मुख्यमंत्री तक सीमित है, अन्यथा कोई वजह नहीं थी कि प्रदेश की नीति-निर्धारण व क्रियान्वयन संबंधित कार्यसमिति की उपेक्षा की जाती।" 'मास ट्रांसफर्स' का शिकवा भी पत्र में दर्ज है और कहा गया है, "यह तालमेल तो कुछ लोगों का कुछ लोगों के लिए है।"

पत्र में कई सवाल भी उठाये गये हैं, मसलन 'चुनाव (पंचायत) करीब-करीब सर पर आ गये हैं। चुनाव में कांग्रेस की क्या नीति होगी? क्या चुनाव दलीय आधार पर होंगे? दलीय आधार पर होंगे, तो टिकट कौन देगा? आदि-इत्यादि। फिर कहा गया कि पत्र में हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों ने यह महसूस किया है कि आप एक सप्ताह में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक उक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलायें।

गहलोत का जवाब: 'माया' ने इस पत्र के संबंध में १७ मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत से जानकारी चाही, तो उनका कहना था, "मैंने भी आज सुबह समाचार पत्रों में पढ़ा है। मुझे अभी तक कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है।" बहरहाल, उन्होंने समाचार पत्रों की कतरनों में दर्ज मुद्दों को देखते हुए बताया कि कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जोशीजी के मुख्यमंत्रित्व के दौरान लिया गया था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार जनतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय से करवाने की जिम्मेवारी प्रदेश संगठन और सरकार की है। गहलोत का कहना था कि जोशीजी ने अपने शासनकाल में इन आदेशों को दो बार टाला, जिसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमेशा विरोध किया। कुछ रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, "श्री जोशी कैसे कहते हैं, यह इकतरफा निर्णय है? उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में उनकी उपस्थिति में सारे कांग्रेसजनों ने इस पर आम सहमति व्यक्त की थी।" बहरहाल, जब गहलोत से माया' ने सवाल किया कि अकाल के दौरान पंचायत चुनाव कहां तक वाजिब है? तो गहलोत का जवाब था, "पंचायत चुनावों की इस घोषणा ने हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को गांव-गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं के जाने से अकाल पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी या तकलीफ?" फिर खुद ही कहने लगे, "ये लोग सारे तंत्र को मजबूत करेंगे। जोशीजी का बयान उनकी राजनीति का हिस्सा है, वह देते रहें बयान, पर माथुर सरकार कांग्रेस के वायदों को पूरा करने में पीछे नहीं रहेगी।"

उधर जोशी की पहल पर बना कांग्रेसियों का समाजवादी मंच अपना प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाने की योजना बना रहा है। १६ मई को इसके आयोजकों ने घोषणा की है कि प्रदेश स्तरीय इस सम्मेलन की तैयारी समिति की बैठक १३ जून को कोटा में होगी, जिसमें केंद्र के पूर्वमंत्री वीएन गाडगिल अथवा केआर गणेशन भाग लेंगे। इस बैठक में हरिदेव जोशी, सांसद नवल किशोर शर्मा, हीरालाल देवपुरा, गुलाब सिंह शक्तावत सहित प्रदेश के लगभग सौ वरिष्ठ कांग्रेसी भी शामिल होंगे।

सत्ताधारी दल के नये समीकरण प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने की क्षमता रखते हैं, जिससे कांग्रेस या तो बहुत शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरकर सामने आयेगी या फिर बहुत बौनी हो जायेगी। फिलहाल, इस वक्त इस बात को मापने का एक ही जरिया है, और वह है, पंचायत चुनावों के परिणाम।

—ओम सैनी

प्रोफेसर अग्रवाल की हत्या

रहस्य रहस्य ही रहेगा ?

मेरठ में गत ३० अप्रैल को हुई प्रोफेसर एसके अग्रवाल की हत्या का रहस्य अभी तक बरकरार है। अग्रवाल मेरठ कालेज में जन्तुविज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्हें सीपीएमटी कोचिंग का महारथी कहा जाता था। पुलिस इस हत्या का सारा दोष लापता चौकीदार जानीवाकर उर्फ निजामुद्दीन उर्फ जितेन्द्र पर मढ़कर तहकीकात बन्द कर चुकी है। पुलिस को अब बस जानीवाकर की तलाश है, जिसके सम्बन्ध में खुद पुलिस ही यह मानकर चल रही है कि वह अब नहीं मिलेगा।

५५ वर्षीय प्रोफेसर अग्रवाल मूलतः कानपुर के निवासी थे। वह १९६९ में मेरठ कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा के अतिरिक्त इकलौता पुत्र अनुराग है जो इन दिनों बंगलोर के इंजीनियरिंग कालेज में तृतीय वर्ष का छात्र है। घटना से १५ दिन पूर्व अनुराग छुट्टी पर मेरठ आया हुआ था। आकर्षक व्यक्तित्व वाले प्रोफेसर अग्रवाल के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि वह आशिक मिजाज थे और गरीबों का काफी शोषण करते थे। प्रो अग्रवाल अपने परिवार के साथ नेहरू रोड स्थित एक साधारण से मकान में रहते थे जो उन्होंने मेरठ में अपनी नियुक्ति के बाद खरीदा था। इन दिनों वह हरनाम दास रोड पर अपनी आलीशान कोठी का निर्माण करा रहे थे। वहां और भी कई कोठियां बन रही थीं। जानीवाकर (अब लापता) इन सबकी चौकीदारी करता था।

घटनाक्रम : २९ अप्रैल को जानीवाकर ने घर जाकर अग्रवाल को सूचना दी कि कुछ लड़कों ने उनकी कोठी की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये हैं। अगले दिन दोपहर १२ बजे अग्रवाल यह कह कर घर से निकले थे कि वह कोठी पर जा रहे हैं। किंतु शाम ६ बजे तक जब प्रोफेसर अग्रवाल घर नहीं लौटे, तो चिन्ताकुल होकर उनकी पत्नी पुष्पा अग्रवाल अपने पुत्र अनुराग के साथ कोठी पर जा पहुंचीं। कोठी के बाहर ही प्रोफेसर का बजाज स्कूटर डीईबी—२६५२ खड़ा था। श्रीमती पुष्पा ने जब कोठी के भीतर जाकर देखा, तो उनकी चीख निकल गयी। एक कमरे में प्रो अग्रवाल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उनकी गर्दन व सर में कई घाव थे, जिनसे खून बहकर फर्श पर जम गया था। लाश के पास ही उनके जूते पड़े थे। दायें हाथ की मुट्ठी में बालों का गुच्छा था, जो प्रोफेसर अग्रवाल और हत्यारे के बीच हुए संघर्ष की ओर संकेत करता था।

पुलिस कार्रवाई : उसी दिन शाम ७ बजे अनुराग अग्रवाल ने थाना सिविल लाइन्स में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने घटनास्थल से एक रक्तरंजित गंड़ासा बरामद किया। कोठी की खिड़कियों के सभी शीशों को सही-सलामत देख, पुलिस को शक हुआ कि कहीं चौकीदार जानीवाकर ने पूर्वनियोजित योजना के तहत प्रो० अग्रवाल की हत्या करने के लिए उन्हें झूठी सूचना तो नहीं दी थी। जानीवाकर की खोज करने पर उसे लापता पाया गया, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। हत्या के कारण के विषय में पुलिस का कहना है, "जानीवाकर का प्रोफेसर अग्रवाल से पैसों के लेनदेन को लेकर पुराना विवाद था। इसी रंजिश में जानीवाकर ने उनकी हत्या की है।"

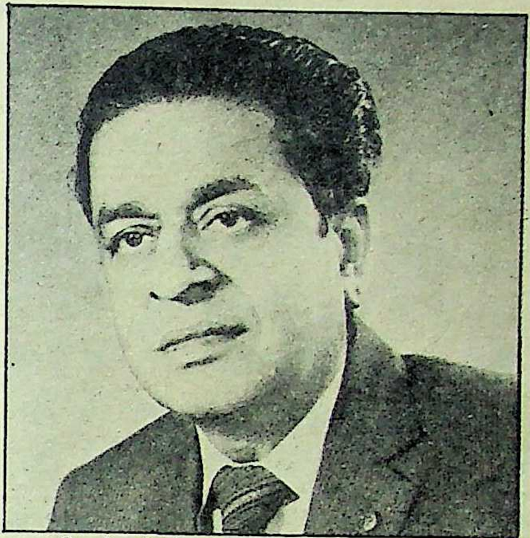

हत्या किसने की ? : प्रो० अग्रवाल

रंजिश का कारण : २८ फरवरी '८८ को जानीवाकर ने थाना सिविल लाइन्स में प्रोफेसर अग्रवाल तथा आदित्य कुमार रस्तोगी के विरुद्ध भादंसं की धारा ३२३/३४२ के तहत एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसने पुलिस को बताया था कि आदित्य रस्तोगी और प्रोफेसर अग्रवाल ने उसके दस हजार रुपये हड़प लिये हैं। पैसे मांगने पर उन लोगों ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा और नौकरी से निकाल दिया है। आदित्य रस्तोगी, प्रो अग्रवाल के मित्र हैं। उनकी कोठी भी प्रो अग्रवाल की कोठी के सामने स्थित है।

पुलिस ने इस मामले में जब रस्तोगी और प्रो० अग्रवाल को थाने बुलवाया, तो थाने में ही प्रो० अग्रवाल, जानीवाकर को गालियां देते हुए मारने पर उतारू हो गये थे। बाद में इस मामले में दोनों पक्षों ने सुलह कर ली थी। महज इसी घटना के आधार पर पुलिस ने प्रो अग्रवाल की हत्या का दोषी जानीवाकर को ठहराकर अपने काम की इतिश्री समझ ली है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जानीवाकर कौन था? कहां का निवासी था? इसकी जानकारी केवल प्रो० अग्रवाल को ही थी। पुलिस को जानीवाकर के ठौर-ठिकाने का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। केवल अनुमान के आधार पर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद आगरा और चम्पारण (बिहार) आदि जगहों पर पुलिस ने उसकी तलाश की है। अब पुलिस के ही वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है, "जानीवाकर का कोई पता हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे खोज पाना नामुमकिन-सा प्रतीत होता है।"

छानबीन के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। लगभग छह माह पहले प्रो० अग्रवाल ने मोहल्ला बकरी निवासी डालचन्द्र की पुत्री सुमन से जानीवाकर की शादी करवायी थी। शादी के वक्त प्रोफेसर अग्रवाल ने डालचन्द्र को जानीवाकर का नाम जितेन्द्र (हिन्दू) बताया था। लेकिन शादी के तीन दिन ही बाद जब सुमन को जानीवाकर के मुसलमान होने की जानकारी मिली, तो वह अपने पिता के पास वापस चली गयी। आश्चर्य की बात यह है कि जानीवाकर की ससुराल वालों को भी उसके ठौर-ठिकाने के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गयी। प्रोफेसर अग्रवाल डालचन्द्र से झूठ क्यों बोले? यह प्रश्न भी उनकी हत्या के साथ अनुत्तरित रह गया है।

दूसरा पहलू : छानबीन के दौरान इस हत्याकाण्ड का एक दूसरा पहलू भी प्रकाश में आया है। पता चला है कि मेरठ कालेज के ही तीन प्राध्यापकों का एक गुट प्रोफेसर अग्रवाल से व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता मानता था। इन लोगों ने घटना से कुछ दिनों पूर्व प्रो० अग्रवाल को धमकी भी दी थी। लेकिन उस धमकी को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ लोगों का मानना है कि प्रो० अग्रवाल के कुछ करीबी दोस्त ही उनकी हत्या के रहस्य को बरकरार रखना जाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि हत्या का रहस्य उजागर होते ही प्रो० अग्रवाल तथा कुछ अन्द वरिष्ठ लोगों के क्रिया-कलापों की वास्तविक जानकारी जनता को मिल जायेगी।

प्रो० अग्रवाल की मुट्ठी में जो बालों का गुच्छा पाया गया था, निश्चय ही वह उनके हत्यारे के बाल होंगे। वे बाल काले तथा चमकीले हैं। पुलिस इस मामले में जानीवाकर को दोषी मानकर चल रही है, जबकि आदित्य कुमार रस्तोगी का कहना है, 'जानीवाकर के बाल भूरे और रूखे थे।'

१० मई को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह मेरठ गये थे। तब 'नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन आफ इंडिया' के अध्यक्ष रोमेश सब्बरवाल सहित तमाम छात्रों तथा मेरठ कालेज के कुछ प्राध्यापकों ने उनसे मांग की थी कि इस कांड की जांच सीआईडी अथवा सीबीआई से करायी जाये। मुख्यमंत्री की ओर से उनको आश्वासन भी मिला था, किन्तु इस हत्याकाण्ड की फाइल अभी तक पुलिस के पास ही मौजूद है।

हत्यारे के 'काले और चमकीले बाल' के रहस्य को उजागर करने में शायद पुलिस को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। प्रोफेसर अग्रवाल के परिवार को उस दिन का इंतजार है, जब इस मामले की फाइल सीआईडी के सुपुर्द की जायेगी। इस मामले में पुलिस के रवैये को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर अग्रवाल की हत्या रहस्य के गर्त में समा जायेगी।

—राजीव सक्सेना, मेरठ से

सांप्रदायिक ताकतें फिर टकराव की राह पर

रामजन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद का मामला एक बार फिर गरमा रहा है। अब तो दोनों पक्ष खुलेआम मरने-मारने की बातें करने लगे हैं। एक पक्ष ने ऐलान किया है कि १४ अक्तूबर को एक लाख मुसलमान अयोध्या पहुंचकर कथित बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, तो दूसरे पक्ष ने धमकी दी है कि वे ऐसा नहीं होने देंगे, भले ही हिंसा का सहारा क्यों न लेना पडे। दोनों पक्ष अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गये हैं। क्या सरकार तभी चेतेगी जब दोनों पक्ष सांप्रदायिक हिंसा की मुकम्मल तैयारी कर चुके होंगे ?

अंजाम खुदा जाने : शहाबुद्दीन

بابری مسجد کا حصول ہمارا مقصد ہے وہاں نماز پڑھنا ہماری عبادت ہے وہاں مارچ کرنا ہمارا جہاد ہے
بابری مسجد کی مخصوص میٹنگ
۲۲ مئی ۸۸ء بروز اتوار منجانب اراکین ایکشن کمیٹی بابری مسجد اجودھیا فیض آباد

फिर टकराव की तकरीरें : फैजाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग

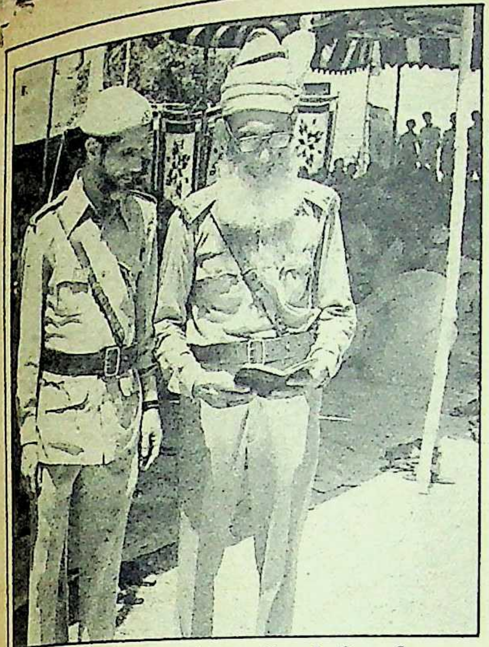

मीटिंग में खाकसार पार्टी के वर्दीधारी सिपाही

फैजाबाद में ऐसी अफवाह थी कि २२ मई को ही एक्शन कमेटी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कूच करेगी। इस अफवाह ने फैजाबाद शहर में तनाव फैला दिया था। २१ मई की रात से ही पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था।

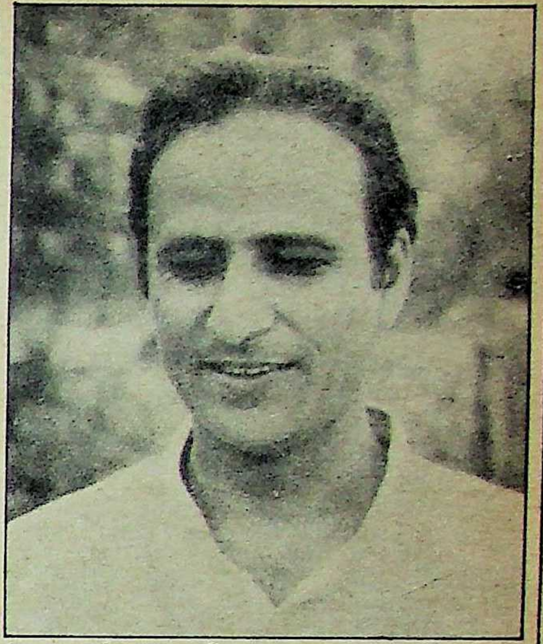

प्रशासन को झांसा : विधायक आजम खान

"मुसलमान अपनी इबादतगाह (बाबरी मस्जिद) में नमाज पढ़ने के लिए १४ अक्तूबर '८८ को 'लांग मार्च' (अयोध्या मार्च) करेंगे। इस दिन देश के कोने-कोने से आये मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। यदि किसी ने 'अयोध्या मार्च' को रोकने की कोशिश की, तो अंजाम बुरे होंगे।" —सैयद शहाबुद्दीन (२२ मई '८८ को फैजाबाद में हुई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक में)

"यदि रामजन्म भूमि पर भव्य मंदिर-निर्माण में सरकार ने जरा भी बाधा डाली, तो इसके परिणाम घातक होंगे। रही 'लांग मार्च' की बात, तो हम किसी भी हाल में 'लांग मार्च' नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हिंसा का रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। बजरंग दल 'लांग मार्च' को रोकने के लिए पूरी तरह समर्थ है।"—अशोक सिंघल (विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव), २८ मई '८८ को कानपुर की एक बैठक में।

इन दो बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार फिर देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की घिनौनी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। हिंदुओं और मुसलमानों के जेहन में जहर घोलने वाली हरकतों का अगर करीब से जायजा लिया जाये, तो साफ दिखायी देने लगता है कि बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि की राजनीति अब खतरनाक दौर में पहुंच गयी है। यदि सांप्रदायिक शक्तियों को अन्य शहरों में मेरठ जैसी वारदात दुहराने से रोकना है, तो राज्य सरकार को तत्काल विवाद के सर्वमान्य समाधान की ओर कदम बढ़ाना होगा।

२२ मई '८८ को फैजाबाद के रीडगंज स्थित निसवां स्कूल में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आगामी १४ अक्तूबर को देश के कोने-कोने से मुसलमानों के जत्थे मार्च करते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। वहां कथित बाबरी मस्जिद पर सामूहिक नमाज अदा की जायेगी। पूर्वाभ्यास के तौर पर पांच सौ मुसलमान १२ अगस्त को फैजाबाद से बाबरी मस्जिद तक जाकर नमाज अदा करेंगे। इस मिनी मार्च में अल्पसंख्यक वर्ग के सांसद, विधायक तथा धर्मगुरु हिस्सा लेंगे।

शपथ पत्र : बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल तथा महाराष्ट्र से आये पांच सौ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बैठक के पूर्व बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की उत्तर प्रदेश शाखा ने एक शपथपत्र भरवाया था। उर्दू में छपे इस शपथपत्र में लिखा था कि एक्शन कमेटी जब कभी भी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान करेगी, हर तरह की कुर्बानी देकर कमेटी के हुकुम की तामील की जायेगी।

देश में होने वाले उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कांग्रेस के अलावा दूसरी किसी भी पार्टी को वोट देने की घोषणा भी फैजाबाद में की। बैठक में सांसद सुलेमान सेठ, मौलाना बुखारी, मौलाना हाशमी, विधायक मुन्ना खां को भी भाग लेना था, पर फैजाबाद के जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव ने इन लोगों के फैजाबाद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

लेकिन सांसद शहाबुद्दीन, विधायक आजम खां, मुजफ्फर हुसैन किछौछवी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रादेशिक संयोजक जफरयाब जिलानी प्रतिबंध के बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दोपहर ग्यारह बजे बैठक स्थल पर पहुंच कर पत्रकारों से मिल चुके थे। हालांकि शाम को जिलाधिकारी ने 'माया' को बताया कि वही लोग फैजाबाद में प्रवेश कर सके थे, जिनके प्रवेश पर प्रतिबंध दोपहर साढ़े बारह बजे हटा लिया गया था।

फैजाबाद में ऐसी अफवाह थी कि २२ मई को ही एक्शन कमेटी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कूच करेगी। इस अफवाह ने फैजाबाद शहर में तनाव फैला दिया था। २१ मई की रात से ही पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सुबह फैजाबाद में सब कुछ सामान्य था, हालांकि वहां के निवासियों के चेहरों पर तनाव और भय भी साफ झलक रहा था।

मुकाबला टला : बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक विनय कटियार भी प्रतिबंध के बावजूद २१ मई की रात अयोध्या तथा फैजाबाद के कई चक्कर लगा चुके थे। २२ मई की सुबह विनय कटियार ने बजरंग दल के बलिदानी जत्थे के पांच सौ कार्यकर्ताओं की बैठक अयोध्या में की। जिस समय फैजाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक में जोरदार तकरीरें चल रही थीं, ठीक उसी समय अयोध्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता रामजन्म भूमि तथा आसपास के क्षेत्र में भगवा झंडा लिए शंखनाद करते हुए फेरियां निकाल रहे थे। विनय कटियार ने 'माया' को बताया, "जो भी व्यक्ति रामजन्म भूमि पर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे।" इसी उद्देश्य से बजरंग दल के बलिदानी कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुलाया गया था।

यह फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरभजन सिंह की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने रीडगंज चौराहे पर प्रदर्शन करने आ पहुंचे 'हिंदू जागरण मंच' के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा लिया। यदि पुलिस थोड़ा भी चूक जाती, तो प्रदर्शनकारी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग में पहुंच जाते और तब कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। ताज्जुब की बात

The perfect
reproduction of
the perfect original—
don't leave it
to chance!

CALL SCANPRINT

Quality that Matters

For any corporate communication—through advertisement, poster, brochure, annual report or calendar—creating the right image counts.

And, the right image emanates from the quality of scanning, processing and printing. SCANPRINT with its latest range of sophisticated scanning and printing equipment and a team of high calibre professionals offers you just that. The right image.

Reliability that Counts

Marketing wars have been lost for want of a nail... nay, due to wrong delivery schedules. In cases which call for prompt service, our own courier will deliver you the job. At your desk. On the dot.

Photo Typesetting

Equipped with advanced Lasercomp photo typesetting unit, SCANPRINT handles typesetting jobs in English, Devnagri and Bengali.

Scanning

SCANPRINT has just installed HELL CHROMOGRAPH 360 ER LASER SCANNER, one of the world's best processing units, for colour separation. This will ensure sharpness and consistency in the reproduction of colour pictures—even during high-speed printing.

Printing

With a fleet of sophisticated machines—two-colour Super Variant, four-colour Heidelberg MOV, Zirkon Web Offset and Hitachi ORP 660—SCANPRINT is fully geared to tackle any printing job—with utmost precision and high skills, comparable with any top quality printer in the country.

Besides, latest folding, stitching, binding and cutting machines give the best possible finish to the final product.

Contact Today

So, when your image is involved—don't take chances. Come to SCANPRINT.

scanprint

Head Office: 281 Muthiganj,
Allahabad 211 003
Phones: 51042, 53681, 55773
Telex: 0540-280 MAYA IN

R K SWAMY/MP/64

SCANPRINT—the perfect image builder

है कि प्रशासन की लाउडस्पीकरों पर पाबंदी के बावजूद इनका इस्तेमाल हुआ और बेहद भड़काने वाली तकरीरें हुईं।

आखिर फैजाबाद जिला प्रशासन ने इतनी भड़काने वाली तकरीरें होने ही क्यों दीं? यह समझ से परे की बात है। फैजाबाद के जिलाधिकारी राम शरण श्रीवास्तव का कहना है कि हमारी असली चिंता थी कि मौलाना बुखारी शहर में न आने पायें, अन्यथा तनाव बहुत बढ़ जाता। सांसद शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि १४ अक्तूबर को प्रस्तावित 'लांग मार्च' में लगभग एक लाख मुसलमान भाग लेंगे। हम हिंसा से बचेंगे। लेकिन हम वही फैसला मानेंगे जो हमारे माकूल होगा।

गहमागहमी जारी: २२ मई को ही रामजन्म भूमि मुक्ति संघर्ष समिति के मार्गदर्शन मंडल के सदस्य रामविलास वेदांती ने घोषणा की कि 'मार्च' जहां से चलेगा, वहीं रोक दिया जायेगा। चाहे इसके लिए बंदूक का सहारा ही क्यों न लेना पड़े? अयोध्या के संत परमहंस रामचंद्र दास जो रामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक भी हैं, 'लांग मार्च' की इस धमकी को महज गीदड़ भभकी मानते हैं। उनका कहना है कि यदि रामजन्म भूमि पर नमाज अदा करने की नीयत से मार्च किया गया, तो हम हर तरह से निपटने को तैयार हैं।

विश्व हिंदू परिषद, रामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति, रामजन्म भूमि संघर्ष समिति तथा बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 'लांग मार्च' के ऐलान को बहुत गंभीरता से लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने आगामी ३ तथा ४ जुलाई को हरिद्वार में एक महासंत सम्मेलन बुलाया है, जिसमें देशभर के सभी हिंदू धर्माचार्य और संगठन के पदाधिकारी भाग लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल के अनुसार, "रामजन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए नक्शा बनाने को देश के कई जाने-माने शिल्पी तैयार हो गये हैं। यदि किसी ने 'लांग मार्च' के जरिये सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।"

इसी बीच रामजन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद को 'आल इंडिया शिया पालिटिकल कांफ्रेंस' ने एक नया मोड़ दे दिया है। कांफ्रेंस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद असगर अब्बास का कहना है कि इस मस्जिद से सुन्नियों का कोई लेना-देना नहीं, यह मस्जिद शियाओं की है। फिर से इस मामले को जिस तरह सड़कों पर लाने का दुष्प्रयास हो रहा है और इसमें नये-नये पेंच डाले जा रहे हैं, उससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

—निशीथ जोशी और भास्कर दुबे फैजाबाद से

'अयोध्या मार्च' नहीं होने देंगे: अशोक सिंघल

> यदि सांप्रदायिक शक्तियों को अन्य शहरों में मेरठ जैसी वारदात दुहराने से रोकना है, तो राज्य सरकार को तत्काल विवाद के सर्वमान्य समाधान की ओर कदम बढ़ाना होगा।

त्रिकालज्ञ
ज्योतिषी

तुझे भविष्य की क्या चिन्ता ?
जा 'लाटरीगुरु' से उ.प्र.लाटरी का टिकट
ख़रीद और लखपति बन जा !

सोमवार गंगा कावेरी
मंगलवार धनलक्ष्मी
बुधवार संगम
गुरुवार आकांक्षा
शुक्रवार जनता
शनिवार रोहिणी
रविवार यू.पी.रैफ़ल

पंजीकृत कार्यालयः
'भाग्यवान' L.I.G. 152,
रतनलाल नगर, कानपुर फ़ोनः 220556

स्टाकिस्ट मे.जे.एन.शर्मा (लाटरी गुरु)
सीसामऊ बाज़ार, कानपुर
फ़ोन- 245047, 245790, 248041

नोटः- केवल 100/-रुपये 'लाटरीगुरु' के नाम ड्राफ़्ट भेजकर पूरे वर्ष घर बैठे लाटरी टिकट प्राप्त करें

निदेशालय उ.प्र. राजकीय लाटरी लखनऊ के सहयोग से

संसद की आबरू खतरे में !

गत बजट सत्र में कांग्रेस-स सांसद केपी उन्नीकृष्णन ने राजीव गांधी की सरकार पर कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में बच्चन-बंधुओं को साढ़े तेईस करोड़ रुपए का आयात लाइसेंस देने में पक्षपात करने का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनौती दी कि यदि वह आरोप सिद्ध कर देते हैं, तो वह अपने मंत्री से इस्तीफा ले लेंगे, अन्यथा उन्हें (उन्नीकृष्णन) संसद से इस्तीफा देना होगा। दोनों पक्षों ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन कांग्रेस-इ सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने जब इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का नोटिस दिया, तो अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अन्य कांग्रेसी सांसद द्वारा प्रस्तुत इस मामले को उन्होंने विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। क्या उन पर सत्तारूढ़ दल का दबाव पड़ा था? यदि इसी तरह वह दबाव में कार्य करेंगे, तो संसद और समूची संसदीय प्रणाली की गरिमा का क्या होगा? इन सवालों को लेकर विपक्षी सांसदों में कैसी हलचल मची हुई है?

बोफोर्स जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की शाकाहारी रिपोर्ट और इस मुद्दे पर १६ घंटे चलनेवाली लंबी बहस के लिए गत बजट सत्र स्मरणीय हो या न हो, किंतु केपी उन्नीकृष्णन के खिलाफ कांग्रेस सदस्य शांताराम नायक द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन का मामला स्वीकार कर उसे समिति के हवाले करने का मुद्दा बेशक ऐतिहासिक है। मजा तो यह है कि कुछ ही समय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जाखड़ ने स्वयं निर्णय दिया था कि इस मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस विवाद के केन्द्रबिंदु भी बहुचर्चित बच्चन-बंधु ही हैं। जंग उनके परममित्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रखर एवं मुखर सांसद उन्नीकृष्णन के बीच है।

मुद्दा १० दिसंबर को लोकसभा में प्रस्तुत प्रथम अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उभरा था। उन्नीकृष्णन ने राजीव सरकार के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में बच्चन बंधुओं को २३.५० करोड़ रुपए का आयात लाइसेंस देने मे पक्षपात किया था। उन्होंने इस मामले में वाणिज्य राज्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी पर सदन में गलतबयानी का आरोप भी लगाया था।

बच्चन बंधुओं और उन्नीकृष्णन के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से काफी दिनों से चलता रहा है। किंतु बच्चन बंधुओं से संबंधित यह मामला संसद में उठाने के उन्नीकृष्णन के सभी प्रयास बराबर विफल होते रहे थे। पिछली अगस्त में कांडला मुद्दे पर आधे घंटे बहस का प्रस्ताव नामंजूर हो गया था। नवंबर में भी इस मसले पर विचार-विमर्श की अनुमति नहीं मिली। अतः दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान जब अवसर हाथ आया, तो उन्नीकृष्णन उसका भरपूर लाभ उठाने से नहीं चूके।

चुनौती स्वीकार: केपी उन्नीकृष्णन

अपनी तेजतर्रार आक्रामक मुद्रा के कारण कांग्रेस खेमे में बेहद खतरनाक माने जानेवाले उन्नीकृष्णन ने प्रधानमंत्री को सीधे लक्ष्य करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। शुरुआत उन्होंने 'तुगलकी प्रधानमंत्री' कहकर की। फिर उन पर विश्वासघात और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया।

तेलुगु देशम के माधव रेड्डी ने जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया तब प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। विपक्ष ने उनकी इस अनुपस्थिति को बहुत बुरा माना। उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने प्रचंड बहुमत के घमंड से उनका घोर अपमान किया है। यह स्पष्टीकरण कि प्रधानमंत्री भोपाल में जिलाधीशों की बैठक में अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सके, विपक्ष की आहत भावनाओं पर मरहम नहीं लगा सका। ऐसी स्थिति में विपक्षी नेता प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को बाध्य थे। संयोग से प्रधानमंत्री का सदन में उसी क्षण प्रवेश हुआ, जब उन्नीकृष्णन अपना पक्ष प्रस्तुत करने जा रहे थे।

प्रधानमंत्री पर आरोप: अपनी तेजतर्रार आक्रामक मुद्रा के कारण कांग्रेस खेमे में बेहद खतरनाक माने जानेवाले उन्नीकृष्णन ने प्रधानमंत्री को सीधे लक्ष्य करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। शुरुआत उन्होंने 'तुगलकी प्रधानमंत्री' कहकर की। फिर उन पर विश्वासघात और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। तदुपरांत सती कांड पर चुप्पी साधने की निंदा की। उन्नीकृष्णन ने लगे हाथ इतालवी फर्म 'स्नैम प्रोजेटी' और प्रधानमंत्री के संबंधों पर भी जोरदार प्रहार किया। ऐसे जबरदस्त हमले के बाद प्रधानमंत्री का गुस्से से भर जाना उतना ही स्वाभाविक था, जितना बदला लेने के मौके की ताक में उनका तत्पर रहना।

गरमागरम बहस जब कांडला मुक्त क्षेत्र और बच्चन बंधुओं को लाइसेंस देने के मुद्दे पर आ पहुंची, तो उन्नीकृष्णन ने दासमुंशी पर संसद को गलत सूचना देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। दासमुंशी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने उन्नीकृष्णन पर भी वही गलत बयानी का

आरोप चस्पा कर दिया। दासमुंशी की बात पूरी होते ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया।

दासमुंशी के एक निकट सूत्र के अनुसार, "जिस ढंग से वाणिज्य राज्यमंत्री ने उन्नीकृष्णन के आरोप का खंडन किया, उससे प्रधानमंत्री को यह अहसास हो गया कि शायद यह उन्नीकृष्णन को पछाड़ने का माकूल मौका है। राजीव गांधी ने स्थिति का लाभ उठाने में राई-रत्ती देर नहीं की। उन्होंने फौरन ऐलान किया कि किसी भी मंत्री ने यदि सदन में गलतबयानी की है तो मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा। मेरी उन्नीकृष्णन से प्रार्थना है कि वह मुझे ऐसी सारी सूचनाएं दें, जिनसे सिद्ध हो कि हमारे मंत्री ने कोई गलत बयान दिया है, वरना उन्हें (उन्नीकृष्णन को) खुद इस्तीफा देना चाहिए।"

जाल बिछा दिया गया। प्रधानमंत्री ने उन्नीकृष्णन पर चुनौती मंजूर करने के लिए लगातार दबाव बनाये रखा। गरमागरमी और भावावेश के उस माहौल में उन्नीकृष्णन ने जोश और गुस्से में न केवल चुनौती स्वीकार कर ली, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। किंतु इसमें एक बात और जोड़ दी कि इस प्रकरण को उनके और दासमुंशी के बीच तक ही सीमित न रखकर इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाये और यदि आरोप सिद्ध होता है, तो स्वयं प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही बच्चन-बंधुओं के व्यापारिक धंधे की भी पूरी जांच-पड़ताल करने की उन्होंने मांग की। किंतु प्रधानमंत्री बड़ी चतुराई से केवल अपने मंत्री का ही नाम लेते रहे। इस प्रकार ऊपर-ऊपर से लड़ाई दासमुंशी और उनके पूर्व कांग्रेस (स) सहयोगी के बीच ही बनी रही।

मामले ने तूल तब पकड़ा, जब सत्र के अंतिम दिनों में यही मसला विशेषाधिकार समिति को भेजने के प्रश्न पर विपक्ष को सदन से बहिर्गमन करना पड़ा। मधु दंडवते के अनुसार, "बहिर्गमन इसलिए नहीं किया गया कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया, बल्कि इसलिए कि मामले को पिछले दरवाजे से विशेषाधिकार समिति के हवाले किया गया और वह भी शासक पार्टी के प्रचंड बहुमत की मदद से और अध्यक्ष के एक मार्च के निर्णय को रद्द करते हुए।"

विशेषाधिकार समिति के सामने कोई मामला ले जाने के पूर्व नियमानुसार नियम २२२ के अंतर्गत एक नोटिस जारी करना आवश्यक है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि प्रथम दृष्टि-साक्ष्य में मुद्दा विशेषाधिकार हनन का बनता है या नहीं। इसके पश्चात अध्यक्ष के सामने तीन विकल्प होते हैं। एक, वह स्वयं फैसला लेकर मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें, दो, मामले को रद्द कर रफा-दफा कर दें और तीन, उसे सदन में बहस के लिए प्रस्तुत कर दें।

मौजूदा मामले में कांग्रेस-इ सदस्य रंगराजन कुमारमंगलम ने विशेषाधिकार हनन नोटिस के द्वारा अध्यक्ष से अनुमति मांगी। अध्यक्ष ने इस विषय पर १ मार्च को अपना लंबा और तर्कपूर्ण निर्णय दिया। उनका कहना था, "जब आरोप लगा, तो वाणिज्य राज्यमंत्री दासमुंशी ने उसका तत्काल खंडन कर दिया था। इसलिए स्थिति का समुचित स्पष्टीकरण हो चुका था।"

अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद यद्यपि आरोपों-प्रत्यारोपों, चुनौतियों का दौर चला, किंतु वह अपने निर्णय से टस-से-मस न हुए। उनका दावा था, "सावधानीपूर्वक मामले पर गौर करने के बाद तथा नियम-परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं कि मामला विशेषाधिकार हनन का नहीं है।" उन्नीकृष्णन के इस दावे से उन्होंने सहमति भी व्यक्त की कि संविधान की धारा १०५ के अंतर्गत भी उन्हें यह संरक्षण प्राप्त है कि अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए संसद में किये गये कथनों के लिए उन्हें दंडित न किया जाये। इसके बाद अधिकांश लोगों की धारणा थी कि मामला रफादफा हो गया।

किंतु धमाका अभी बाकी था। अचानक सदन में वह प्रस्ताव कांग्रेस-इ सांसद शांताराम नायक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे पहले किसी ने 'असंगत' तो किसी ने 'शरारतपूर्ण' करार दिया था। इस प्रस्ताव में विशेषाधिकार समिति से उन्नीकृष्णन के आरोपों की विस्तृत जांचकर आगामी मानसून सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

मैं लाचार हूं: बलराम जाखड़

जब पहले लोकसभा अध्यक्ष मामले पर अपना निर्णय दे चुके थे, तो दुबारा प्रस्ताव को स्वीकारना अपने ही निर्णय को रद्द करना है। जिस ढंग से अध्यक्ष ने अपनी लाचारी दिखायी, उससे यह दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बनी, चाहे वह सच हो या गलत, कि अपने प्रचंड बहुमत के साथ शासक दल उनकी गर्दन पर सवार था।

बहुमत का दबाव: साफ है कि बीच के सप्ताहों में लोकसभा अध्यक्ष ने अपना विचार बदल दिया था। जनता सांसद जयपाल रेड्डी के अनुसार, "जब पहले लोकसभा अध्यक्ष मामले पर अपना निर्णय दे चुके थे, तो दुबारा प्रस्ताव को स्वीकारना अपने ही निर्णय को रद्द करना है। जिस ढंग से अध्यक्ष ने अपनी लाचारी दिखायी, उससे यह दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बनी, चाहे वह सच हो या गलत, कि अपने प्रचंड बहुमत के साथ शासक दल उनकी गर्दन पर सवार था। यदि इस पक्षपातपूर्ण तरीके से ऐसे विवादग्रस्त प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को सौंपे जायेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी रह जायेगी कि शासक दल के सदस्यों से पूर्णतया भरी यह समिति दूध-का-दूध और पानी-का-पानी कर सकेगी? यह संदेह भी लोगों के मन में घर कर गया है कि विशेषाधिकार समिति बोफोर्स मामले में गठित समिति से कुछ भिन्न नहीं होगी।"

अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के वाक आउट के बाद कहा, "मुझे नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। पूरे सदन ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की थी। मैं भला क्या कर सकता था? कार्रवाई विवरण को देखिये। खुद उन्नीकृष्णन ने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग की थी। सबने यही कहा था। सदन में चुनौती देनेवाले को मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

"यह उक्ति अपने आप में बिलकुल उचित है," बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता इन्द्रजीत गुप्त ने टिप्पणी करते हुए कहा, "इसीलिए जब मामला पहले पहल कुमारमंगलम द्वारा उठाया गया, तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। किंतु अध्यक्ष के पूर्व-निर्णय के विपरीत मामले को विशेषाधिकार समिति में देना इस विशेष समिति को उसके क्षेत्र के बाहर का काम सौंपना होगा।"

जहां तक समिति के कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, नियम ३१४ के तहत उसका काम है, विशेषाधिकार के प्रत्येक प्रश्न की जांच करना। दूसरे शब्दों में केवल विशेषाधिकार के प्रश्न की ही समिति जांच कर सकती है। चूंकि, मामला पहले ही विशेषाधिकार का नहीं माना गया है, इसलिए विपक्ष का विचार है कि अब केवल किसने क्या कहा, इसी की सामान्य जांच होगी। यह न केवल अप्रत्याशित है, बल्कि समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी।

विपक्ष का मानना है कि सदन के लिए इस बात पर विचार करना कि सच बोला गया है, अथवा नहीं, सर्वथा उचित है। किंतु सदस्यों के बीच दी गयी चुनौतियों को देखना और उन पर विचार करना उसका काम नहीं है। "दरअसल, संसद की प्रतिष्ठा

ही दांव पर लग गयी है। जब अनगिनत मुद्दों को बिना किसी विचार विमर्श के खतम कर दिया जाता है, जब महत्वपूर्ण मसलों के लिए अपर्याप्त समय निर्धारित किया जाता है, तब क्या संसद को ऐसे गौण मुद्दों में समय बरबाद करना उचित है?" यह टिप्पणी एक दुखी और वृद्ध कांग्रेस सांसद की थी। उन्होंने याद दिलाते हुए आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष एचएस हेगड़े ने दस वर्ष पूर्व सदस्यों को समय बरबाद करने के लिए फटकारते हुए कहा था कि संसद के प्रत्येक मिनट का खर्च ६० हजार रुपए होता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब यह खर्च कहीं अधिक होगा।

मामला एक और बात को लेकर भी ऐतिहासिक है। शांताराम नायक का यह प्रस्ताव नियम १८४ के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। किंतु नियम १८६ के अनुसार किसी भी विषय को एक सत्र में दो बार न तो उठाया जा सकता है, न उस पर दुबारा बहस की जा सकती है। चूंकि, कुमारमंगलम की नोटिस पर इसी सत्र की शुरुआत में विचार-विमर्श और निर्णय हुआ था, इसलिए इस मसले को दुबारा उठाना और उस पर निर्णय लेना नियम विरुद्ध है। दूसरे, जयपाल रेड्डी के अनुसार, "प्रस्ताव में विवरण के रूप में कोई तार्किक अथवा विषय संबंधी बात नहीं है, पर नायक के प्रस्ताव में इसकी भरमार है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस कदम का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं।"

उल्लेखनीय है कि यद्यपि मामला समिति को सौंप दिया गया है, किंतु सदन ने यह निर्धारित नहीं किया है कि वह रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करेगी। विपक्ष के वाक आउट के बाद भी सदन में उपस्थित रहनेवाले मुस्लिम लीग के सांसद जीएम बनातवाला ने मामले को सहजतापूर्वक सुलझाने पर जोर देते हुए कहा, "यदि जांच समिति इस नतीजे पर पहुंची कि वास्तव में विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो क्या उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सांसत में नहीं पड़ जायेंगे? क्योंकि वह स्वयं पहले इस नतीजे पर पहुंचे थे कि विशेषाधिकार हनन नहीं हुआ है" किंतु सत्ता पक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

सवाल-दर-सवाल : इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि समिति ने उन्नीकृष्णन को दोषी ठहराया, तो क्या उनसे इस्तीफे की मांग की जायेगी? यदि उन्नीकृष्णन ने ऐसा करने से इनकार किया, तो क्या होगा? क्या सदन दो सदस्यों के बीच चुनौतियों को ध्यान में रख उन्नीकृष्णन को जबरन सदन की सदस्यता से बाहर कर देगा? इस दौरान अध्यक्ष की अपनी क्या भूमिका होगी? नि:संदेह शासक दल विपक्ष को सबक सिखाने पर उतारू है, किंतु उसका आचरण और कार्यशैली उस सरकार की निराशा और बौखलाहट की परिचायक है जो स्वयं कथित भ्रष्टाचार और घोटालों के चक्रव्यूह में फंसी है। बात यहीं खतम नहीं होती। यदि उद्देश्य विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना आरोपों का भंडाफोड़ करना और बेबुनियाद आरोप न लगाने की स्वस्थ परंपरा को बरकरार रखना होता, तो सर्वप्रथम सरकार और प्रधानमंत्री ने इस मामले में इतने अधिक नियमों-परंपराओं का उल्लंघन न किया होता। साथ ही उन्होंने बनातवाला के मामले को रफादफा करने के प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया होता। जैसाकि बनातवाला ने संकेत किया था, "विपक्ष यों भी इस मसले को लेकर देश के सामने बेपर्द हो चुका था, क्योंकि पहले समिति के पास मामला ले जाने के सवाल पर तकनीकी मुद्दे का सहारा लेकर वह उससे बचना चाह रहा था। इसीलिए विपक्ष का मानना है कि नायक के प्रस्ताव को जिस सुनियोजित तरीके और पिछले दरवाजे से मंजूर कराया गया है, उससे उजागर होता है कि सरकारी मंशा उन्नीकृष्णन जैसे अपने प्रखर आलोचक विपक्षी नेता को बदनाम कर इस्तीफा देने को बाध्य करना है।

राजीव गांधी के उदय के बाद कांग्रेस-इ की रणनीति यही रही है कि येन-केन-प्रकारेण वरिष्ठ मुखर विपक्षी नेताओं को संसद से बाहर रखा जाये। इसकी पहली झलक गत लोकसभा चुनावों के दौरान तब मिली जब अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम जेठमलानी आदि को सदन से बाहर रखने की चाल सफल हुई थी। वर्तमान रणनीति इसका ही अगला चरण है। इसका लक्ष्य वे सांसद हैं जो सरकार के लिए हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। यदि यह सही है, तो उन्नीकृष्णन की बलि पहली होगी, आखिरी नहीं।

राजीव की रणनीति : राजीव गांधी के उदय के बाद कांग्रेस-इ की रणनीति यही रही है कि येन-केन-प्रकारेण वरिष्ठ मुखर विपक्षी नेताओं को संसद से बाहर रखा जाये। इसकी पहली झलक गत लोकसभा चुनावों के दौरान तब मिली जब अटल बिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम जेठमलानी आदि को सदन से बाहर रखने की चाल सफल हुई थी। वर्तमान रणनीति इसका ही अगला चरण है। इसका लक्ष्य वे सांसद हैं तो सरकार के लिए हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। यदि यह सही है, तो उन्नीकृष्णन की बलि पहली होगी, आखिरी नहीं।"

नायक के प्रस्ताव की स्वीकृति, उस पर अगली कार्रवाई और कांग्रेसजनों का हर्षोल्लास श्रीमती गांधी के खिलाफ छठी लोकसभा में उठाये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव की याद दिलाते हैं। उस समय भी बात जान के पीछे पड़ जानेवाली ही थी। उस समय शासक जनता पार्टी भी प्रचंड बहुमत में थी, जैसा आज कांग्रेस-इ है। पिछली घटना जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत सिद्ध हुई थी। श्रीमती गांधी ने अपने निष्कासन का बदला सरकार गिराकर लिया था। क्या इस मामले का अंतिम परिणाम भी उस जैसा होगा? क्या वर्तमान बवंडर राजीव गांधी के लिए इतना ही खतरनाक साबित होगा?

संकेत साफ नजर आने लगे हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों में भी यह चर्चा आम है कि सरकार विशेषाधिकार समिति के गठन में परिवर्तन के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उसकी मशा उन्नीकृष्णन के खिलाफ लगे आरोपों को हर हाल में सिद्ध करने की है। ज्ञात रहे कि विशेषाधिकार समिति में शासक दल व विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। बोफोर्स समिति में शामिल अन्नाद्रमुक के सांसद सदस्य अल्लादि अरुणा की विरोधपूर्ण टिप्पणी के कटु अनुभव के पश्चात सरकार अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। कहा जाता है कि बाहर किये जानेवाले सदस्यों में मार्क्सवादी पार्टी के जानेमाने सांसद व बैरिस्टर सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग होंगे। किंतु ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए विपक्ष क्या कदम उठा सकता है?

विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक संशोधन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश किया है। इसमें मांग की गयी है कि उन्नीकृष्णन को सभी जरूरी कागजात पेश करने का अधिकार दिया जाये। इसके अलावा गवाहों से जिरह करने का और कानूनी मदद लेने का मौका मिलना चाहिए। "विशेषाधिकार समिति को जो इस मसले की जांच कर रही है, बच्चन बंधुओं के कांडला संबंधी धंधों की भी पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए," एक रुष्ट विपक्षी नेता ने कहा। एक अन्य ने टिप्पणी की, "सभी साधनों के बावजूद मंत्री तक गलत बयान जारी करते हैं। आशा है, भविष्य में उनके खिलाफ भी जांच बिठाई जायेगी।"

दोनों खेमों में जोशोखरोश है। दासमुंशी खेमे के एक नेता ने 'माया' से कहा, "उन्नीकृष्णन घोर उत्पाती है। बेमतलब तोड़फोड़ करना उनकी पुरानी आदत है। उनके झूठ की पोल खोलने का समय आ गया है।" किंतु उन्नीकृष्णन के एक समर्थक सांसद ने जवाब में कहा, "देखना है, अंत में विजय किसकी होती है।" एक मसखरे ने हंसकर कहा, "इस सरकार में जो न हो, वह थोड़ा है। इसने न तो इतिहास से कुछ सीखा है, न वर्तमान से। और-तो-और, मतदाताओं की भी यह सरासर उपेक्षा कर रही है।" ऐसी स्थिति को नि:संदेह कांग्रेस-इ के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता।

—रंजना कक्कड़

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

क्या श्रीराम उद्योग समूह संकट में है?

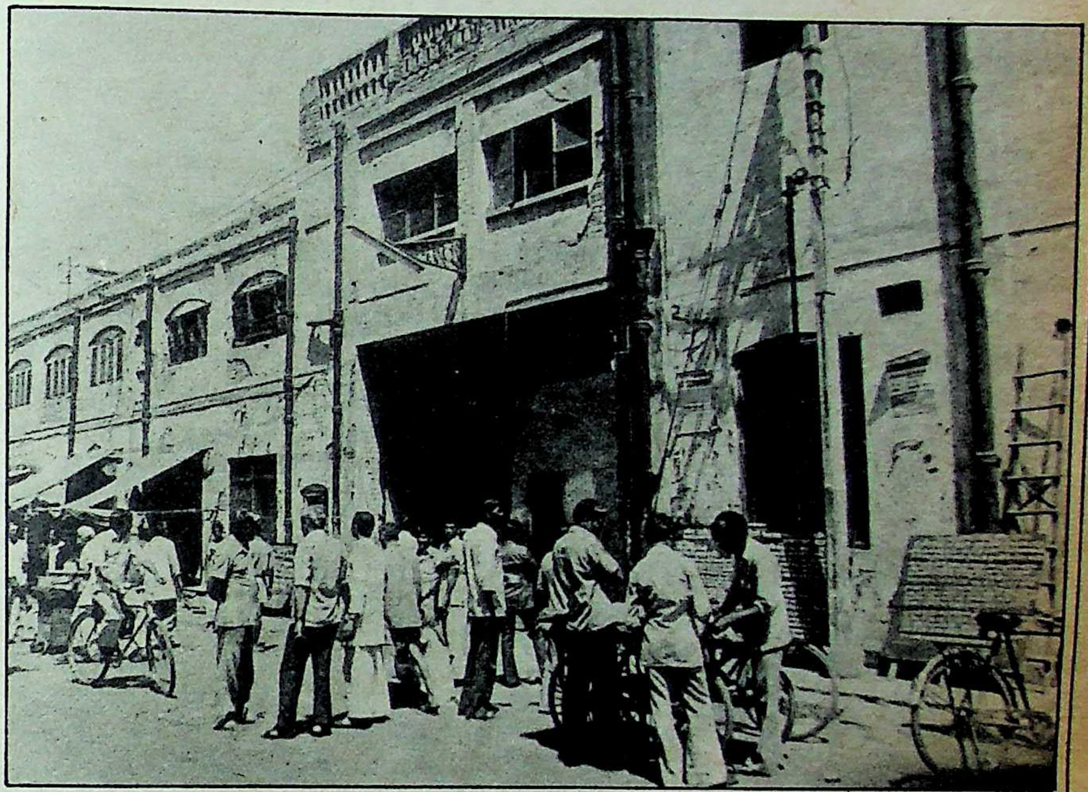

घाटे की कंपनी : दिल्ली स्थित डीसीएम की मिल के बाहर हड़ताली कर्मचारी

"कुछ समय से बाजार पर्यवेक्षकों में अटकलबाजियां चल रही हैं कि क्या डीसीएम (दिल्ली क्लाथ मिल्स) एक अकेली कंपनी के रूप में कायम रहकर फलफूल सकती है अथवा नहीं? कभी-कभी तो लगने लगा था कि कंपनी अपने खुद के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जायेगी। शायद हाल में पुनर्गठित प्रबंध टीम उसको बचाने में कामयाबी हासिल कर सके, किंतु बोझ अधिक हैं और समय कम," यह टिप्पणी प्रनंजय गुहा ठाकुराता ने बम्बई की 'बिजनेस अपडेट' पत्रिका में की है।

इस व्यावसायिक परिवार के सदस्यों के बीच लम्बे विचार-विमर्श और मतभेदों के बाद गत जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस कंपनी में नयी प्रबंध-व्यवस्था कायम की गयी। सिद्धार्थ श्रीराम को डीसीएम टेक्सटाइल्स के कामकाज का कार्यभार सौंपा गया। कदाचित अपने टेक्सटाइल्स कारखानों को पुनः सुचारु रूप से चलाने के लिए कंपनी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वे बेहद खस्ताहाल हैं। चचेरे भाइयों में सबसे बड़े बंसीधर फर्टीलाइजर्स बनानेवाली इकाइयों और सेंथेटिक उत्पादों, मसलन प्लास्टिक, रेयन व सीमेंट आदि बनानेवाली इकाइयों के कर्ता-धर्ता बनाये गये हैं। उन्हें दिल्ली स्थित मुख्यालय की देखरेख का संपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया है। विनय भरतराम को दिल्ली में तिरसठ करोड़ मूल्य की भूमि में फैले डीसीएम की स्वतंत्र भारत मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा वह इलेक्ट्रानिक्स और इंजीनियरिंग सामान बनानेवाली इकाइयों की देखरेख भी करेंगे। अरुण भरतराम अब केवल निदेशक-मंडल के एक सामान्य सदस्य ही रह गये हैं।

घाटा ही घाटा: क्या इससे कंपनी की डगमगाती नैया पार हो सकेगी? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इस औद्योगिक समूह के नियंत्रण में चलनेवाली तमाम कंपनियों के गत अनेक वर्षों के अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। श्रीराम की पांच टेक्सटाइल मिलों की हालत सबसे खस्ता है। इन कंपनियों का कुल घाटा प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया है। १९८१ में जो घाटा ५ करोड़ था, वह अगले साल ९ करोड़ और उसके अगले साल साढ़े सात करोड़ और १९८४-८५ में पांच करोड़ से अधिक हो गया था। अगले दो वर्षों में यद्यपि यह घाटा थोड़ा कम होकर ढाई करोड़ तक पहुंच गया था, किंतु ऐसा लगता है कि इस वर्ष घाटे में और वृद्धि होगी।

अपने दूसरे उत्पाद रेयन में भी कंपनी को भारी घाटे का सामना करना पड़ता है। रेयन को मुख्य रूप से टायर बनाने में अब तक इस्तेमाल किया जाता था, किंतु अब उसका स्थान तेजी से नायलान लेता जा रहा है। इससे इस उत्पाद की घरेलू बाजार में अधिक मांग की संभावना नहीं रहेगी। कंपनी के प्लास्टिक कारखानों की स्थिति भी सोचनीय है। रसायन बनाने की इकाई अवश्य भलीभांति चल रही है, किंतु नयी कम्प्यूटर इकाई अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से बहुत पीछे है। रसायनों एवं फर्टीलाइजरों के क्षेत्र में एक समय कंपनी की तूती बोलती थी, किंतु फर्टीलाइजर बनानेवाली ज्यादातर कंपनियां आज घोर विपत्ति का सामना कर रही हैं, क्योंकि उत्पादन की तुलना में मांग कम है।

ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में क्या श्रीराम का कोई ऐसा उत्पाद है, जिसका अच्छा बाजार होने के साथ-साथ भारी मुनाफा भी हो? शायद उसकी जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी टोयटा के सहयोग से बन रही गाड़ियों (बस, ट्रक, जीप आदि) की नयी परियोजना इस मामले में सफल सिद्ध हो सके। किंतु व्यावसायिक गाड़ियों की मांग में भी कुछ समय से गिरावट आयी है। कुछ वर्ष पूर्व टाटा ने अपनी गाड़ियों का बाजार बढ़ाने की दुबारा कोशिश की थी, जिसमें विफलता हाथ लगी। एक अन्य प्रमुख गाड़ी-निर्माता अशोक लेलैंड का भी उत्पादन मांग से अधिक है। कुछ लोगों का विचार है कि हल्की गाड़ियां बनानेवालों को इस बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसलन, मैटाडोर, टैम्पो और छोटी ट्रकें, आदि कम ईंधन पर चलनेवाली गाड़ियों की मांग अधिक है।

डीसीएम टोयटा फर्म भरतराम और उनके दो पुत्रों—विनय भरतराम और विवेक भरतराम (अरुण तीसरे पुत्र हैं) के नियंत्रण में है। संभव है, यह फर्म सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी साबित हो। इस समूह की जय-इंजीनियरिंग फर्म जो अपने पंखों, सिलाई-मशीन और बिजली के सामानों के लिए प्रख्यात है, अवश्य निरंतर प्रगति करती जा रही है। इस कंपनी की बागडोर अभी भी बड़े भाई चरतराम के हाथ में है। उनकी अपने छोटे भाई भरतराम से पटरी नहीं बैठती। उनका आपसी संघर्ष कुछ वर्ष पूर्व सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया था।

घाटा क्यों ? : श्रीराम के अनेक उद्यम घाटे में क्यों चल रहे हैं? एक समय के नामीगिरामी व्यावसायिक घराने की उच्च प्रतिष्ठा सट्टा-बाजार में घट गयी है? क्या इसके लिए केवल निदेशक जिम्मेदार हैं? अथवा यह व्यावसायिक घराने के परस्पर बिगड़ते आपसी संबंधों का परिणाम है? दोनों भाई—भरतराम और चरतराम में पटती नहीं, यह अब जगजाहिर है। क्या उनके बेटे मिलजुलकर काम कर रहे हैं? अथवा क्या उनमें से

कोई व्यवसाय कैसे तरक्की करता है?

लाला भरतराम

यदि आप से कहा जाये कि एक व्यावसायिक फर्म के पास अब लगभग १००० करोड़ की परिसम्पत्ति है, किंतु कंपनी-संचालनों ने अपनी जो पूंजी लगायी (जब फर्म का गठन किया गया) वह १५ लाख भी नहीं थी, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी और जानकारी लें, मसलन कंपनी का नियंत्रण करनेवालों की मौजूदा चुकता-पूंजी का प्रतिशत क्या है, अथवा उन्होंने गत अनेक वर्षों में निदेशक के वेतन और कमीशन के रूप में कुल कितनी रकम हथियायी है? यदि यह पता चले कि नियंत्रणकर्ताओं की चुकता पूंजी ५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं और वेतन-भत्ता, लाभ पर कमीशन आदि (इसमें शेयरों का लाभांश शामिल नहीं) पर उन्होंने २ करोड़ से अधिक की कमाई की है, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिकांश निदेशकों के निजी नियंत्रणवाले अलग व्यवसाय भी होते हैं। निजी व्यवसाय अपेक्षाकृत बड़ी कंपनी पर निदेशक के दबदबे से दिन-दूना रात चौगुना बढ़ता है, क्योंकि यही बड़ी कंपनी सामानों को खरीदती और बेचती है।

इस प्रक्रिया में करोड़ों का लेन-देन होता है और खरीद-फरोख्त में शामिल हर बिचौलिये (जो क्रय या विक्रय एजेंट के नाम से जाना जाता है) को मुनाफे पर अच्छा कमीशन मिलता है। ऐसे कमीशन एक वर्ष में कुछ करोड़ होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे धंधे में कितनी कमाई है। हां, यह तभी आसानी से संभव है, जब ऐसी व्यापारिक कंपनी का मालिक या प्रबंधक किसी ऐसी भीमकाय कंपनी की भी महत्वपूर्ण हस्ती हो, जो खरीद का आर्डर देती हो।

कमाई के अन्य रास्ते भी हैं। मान लीजिए, एक कंपनी शेयर बेचना चाहती है या ब्याज पर बाजार से कर्ज लेना चाहती है (कंपनियां प्रायः कर्जा लेती और उसे चुकाती रहती हैं, क्योंकि उनको 'कार्यकारी पूंजी' की जरूरत पड़ती है) और 'यदि कोई निदेशक लेन-देन का काम करने वाली कंपनी (मसलन वित्तीय कम्पनी) खोलकर आकर्षक शेयरों की खरीद-फरोक्त करता है, तो उसके लिए मोटी कमाई करना मुश्किल नहीं। मान लीजिए, कंपनी शेयर बेचना चाहती है, जिसका बाजार मूल्य ऊंचा है (खरीद की तुलना में), तो आप बड़ी संख्या में उन शेयरों को खरीद कर अपने ग्राहक को अच्छे-खासे मुनाफे पर बेच सकते हैं।

किसी बड़ी कंपनी का निदेशक बनने के बाद कमाई के रास्तों की कमी नहीं होती। प्रायः सभी महत्वपूर्ण निदेशक तमाम संभव रास्तों का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में खुद बड़े व्यवसायी बन जाते हैं। बड़ी कंपनियां अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ाती रहती हैं, पहले उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर, फिर अधिक मुनाफा कमानेवाले अन्य सामानों का उत्पादन करके। इस प्रकार वे विभिन्न उत्पादों के बाजार के बड़े भाग पर कब्जा करके एक भीमकाय रूप धारण कर लेती हैं। यदि उसे अपना सामान बनाने के लिए किसी वस्तु की बड़ी मात्रा में दरकार होती है, तो उसका उत्पादन भी वह स्वयं करने लगती है, जो सस्ता पड़ता है। इससे दूसरी फर्मों पर निर्भरता कुछ कम हो जाती है और उस वस्तु पर उसका खुद का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार मुनाफा बढ़ जाता है।

यह 'धंधे' का एक खेल कहा जाता है। व्यवसायी का उत्तर होगा कि उसका मकसद ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा कमाने का है। लेकिन इसमें बुरा क्या है? यदि वह संयुक्त साझेवाली कम्पनी है, तो शेयरधारियों को मुनाफे का लाभ वार्षिक लाभांश से प्राप्त हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, राष्ट्र को अतिरिक्त उत्पादन मिल रहा है जो अर्थशास्त्र में 'राष्ट्रीय आय' कहलाता है। इ सब से सभ्यता का उन्नयन होता है। अंतत समाज और उपभोक्ता ही फर्म के उत्पादों इस्तेमाल करता है।

यह कहना भी गलत होगा कि तमाम बड़े व्यावसायिक घराने या सभी निदेशक धोखाधड़ी करते हैं। अनेक बड़े व्यवसायियों असाधारण क्षमता का परिचय दिया है। यह सही है कि उनको दूसरों की अपेक्षा अधिक मौके हासिल हुए हैं, किंतु ऐसे भी व्यवसायी है, जिन्हें सुविधाएं हासिल थीं, किंतु वे फल-फूल कर बड़े नहीं बन सके।

अर्थशास्त्री और व्यवसायी कहेंगे कि आपकी सफलता आपकी कार्यकुशलता और क्षमता पर निर्भर करती है। एक अर्थशास्त्री ने भारत के एक उच्चकोटि के व्यावसायिक घराने की कार्यकुशलता की एक कहानी सुनायी। वह कंपनी के सलाहकार थे। उन्हें मूंगफली के मूल्यों की हर हफ्ते भविष्यवाणी करने के लिए मोटी तनख्वाह मिलती थी। मकसद यह था कि मूंगफली सस्ती होने पर बड़ी मात्रा में खरीद ली जाये और उसे वनस्पति खाद्य तेल के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाये।

५२ सप्ताहों में मात्र ३ में सलाहकार की भविष्यवाणी पूरी या आंशिक रूप से सही साबित हुई। उन्हें इतनीं कोफ्त हुई कि उन्होंने कंपनी छोड़ने की ठान ली। किंतु कंपनी के प्रबंध-निदेशक ने उलटा उनका वेतन बढ़ा दिया। सलाहकार ने दुबारा जब कहा कि अपनी अधिकतर गलत भविष्यवाणियों से उन्हें बड़ी ग्लानि है और वह विदा लेना चाहते हैं तो प्रबंध-निदेशक ने यह पते की बात कही, "दो हफ्ते आपकी भविष्यवाणी सही उतरी और हमने उसके अनुसार अपनी खरीदारी की। हमको उससे ६० लाख से अधिक का लाभ हुआ। जब हमने शेष सप्ताहों में खरीदारी की और कुछ रकम गंवाई, तो भी कुल घाटा १२ लाख से अधिक नहीं हुआ। इ प्रकार आपसे ४८ लाख का मुनाफा हमें हुआ है। अब तक हमने आपको वेतन के रूप में कुल एक लाख अदा किया है, इसलिए आपकी एक सही भविष्यवाणी भी आपकी वेतन-वृद्धि के लिए काफी है।"

यह एक मिसाल है कि व्यवसाय में कार्यकुशलता कैसे आती है। फौरी लाभ-हानि के आधार पर फैसला लेने की योग्यता ही काफी नहीं, बल्कि यह समझदारी भी जरूरी है कि लंबे समय के लिए लाभप्रद क्या है?

श्रीराम अपनी कार्यकुशलता के लिए ज्ञाने जाते हैं, वरना लाला श्रीराम इतने विशाल साम्राज्य की नींव कैसे डाल जाते?

उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो स्थिति आज जैसी आसान नहीं थी। तब निदेशक आसानी से आज की तरह मोटी रकम नहीं बना सकते थे। पूंजी के लिए लोगों से धन एकत्र करना बड़ा कठिन काम था। तब न तो इतना बड़ा सट्टा बाजार था और न सरकारी सहायता। भारतीय व्यवसायियों के सामने कांटे की प्रतिद्वंद्विता अलग थी।

किंतु कल और आज में बड़ा अंतर है। श्रीराम की सातवें दशक के आरंभ में जो स्थिति थी, वह आज नहीं रह गयी है। अपनी कुल बिक्री में चौथे से चौदहवें नम्बर पर वह पहुंच गयी है। टाटा, बिड़ला और रिलायंस से आज वह काफी नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीराम उद्योग समूह के लिए आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद हो गये हैं।

> **श्रीराम अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं, वरना लाला श्रीराम इतने विशाल साम्राज्य की नींव कैसे डाल जाते? उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तो स्थिति आज जैसी आसान नहीं थी। तब निदेशक आसानी से आज की तरह मोटी रकम नहीं बना सकते थे। पूंजी के लिए लोगों से धन एकत्र करना बड़ा कठिन काम था। तब न तो इतना बड़ा सट्टा बाजार था और न सरकारी सहायता। भारतीय व्यवसायियों के सामने कांटे की प्रतिद्वंद्विता अलग थी।**

क्या इसका अर्थ यह है कि चंद पुराने भीमकाय व्यावसायिक समूह कमजोर हो रहे हैं और नये-मसलन धीरूभाई अंबानी, मनु छाबड़िया या विजय मलैया मजबूत हो रहे हैं? अथवा पुराने लोग व्यवसाय में अधिक सक्षम और कुशल थे और नये लोग अपनी आधुनिक शिक्षा-दीक्षा, राजनीतिक संबंधों और धन कमाने के उपर्युक्त गुरों की जानकारियों के बावजूद उतने सक्षम नहीं हैं?

—कुमारेश चक्रवर्ती

हरेक अपने अलग व्यवसाय (समूह के एक भाग के रूप में नहीं) को फैलाने-बढ़ाने में लगा है? इसका जवाब निम्न तथ्यों से ही मिल सकता है।

डीसीएम टोयटा की मिसाल लें। पिता भरतराम अपने दो बेटों सहित इस उभरते कारखाने की देखरेख से जुड़े हैं। उषा इंटरनेशनल अपेक्षाकृत नयी कंपनी है, जिस पर चरतराम और उसके पुत्र सिद्धार्थ श्रीराम का नियंत्रण है। इन्हीं पिता-पुत्रों का श्रीराम रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज और श्रीराम होंडा पावर इक्विपमेंट पर भी नियंत्रण है।

भरतराम और उनके एक पुत्र का डीसीएम टोयटा के अलावा—श्रीराम बियरिंग्स श्रीराम निडिल बियरिंग, एसआरएफ निप्पो और श्रीराम फाइबर्स पर भी नियंत्रण है। इसका मतलब है कि डीसीएम के अलावा समूचा व्यवसाय व्यापक पारिवारिक दायरे से अलग होकर आज क्रमशः पिता और पुत्र के उद्यम का रूप धारण करता जा रहा है।

श्रीराम के पराभव का एक अन्य कारण है, राजनीतिक परिदृश्य में राजीव गांधी के आगमन के बाद बने नये समीकरण। यदि कुछ पुराने महारथियों का भुजबल घट जाये और उनका स्थान कुछ उभरते नये व्यवसायियों की पीढ़ी ले ले, तो आश्चर्य नहीं।

गत कुछ वर्षों से अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेशों को (एनआरआई) और कुछ पारंपरिक जमे जमाये व्यावसायिक घरानों का संघर्ष जारी है। दुर्लभ विदेशी मुद्रा को देखते हुए एनआरआई बेहतर स्थिति में है। उनकी जमा-पूंजी अथवा विदेशों से प्राप्त कर्ज की रकम पाउंड या डालर में है। अपनी उत्पादक इकाइयों के लिए विदेशों से मशीनें, कच्चा माल और आवश्यक जिन्सें बिना कठिनाई के वे खरीद सकते हैं। इस संबंध में अनेक भारतीय व्यसायियों के लिए कठिनाइयां सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पैदा की हैं। यदि श्रीराम विदेशों से मशीनें आदि खरीदना चाहें, तो न केवल आयात लाइसेंस लेना जरूरी है, बल्कि किसी सरकारी वित्तीय संस्थान से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसकी अनुमति आर्थिक, राजनीतिक पहुंच और संबंधों पर निर्भर करती है।

बाजार का बदलता रुख: एक महत्वपूर्ण मुद्दा बाजार का भी है। आज देश के संपूर्ण उत्पादों का ढांचा बदल गया है, नये उत्पाद बाजार में आ गये हैं और कुछ पुराने उत्पादो की भागीदारी घट या बढ़ गयी है। देश का बढ़ता-फैलता बाजार मुख्यतः धनी उपभोक्ताओं से संबंधित है जो सदैव बेहतर तकनीक, नफीस और लोकप्रिय ब्रांड का सामान खरीदना पसंद करते हैं। इस संदर्भ में विदेशी सहयोग और व्यवसायी का समयानुकूल अपने उत्पाद में परिवर्तन कारगर सिद्ध होता है। यदि वह किसी वस्तु की भावी बाजार मांग को समय पर समझने में नाकाम रहता है और दूसरों की तुलना में अपना उत्पादन पहले नहीं शुरू करता, तो उसके प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़कर बाजार के अच्छे-खासे भाग को हथिया लेते हैं। इसके अलावा उसकी कुल लागत पूंजी उसके प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम नहीं हो सकती। अर्थात उत्पाद की कीमत प्रचलित कीमतों से कम नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में वह घटी कीमत के असाधारण लाभ के रूप में बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके फलस्वरूप उसका कुल उत्पादन उसकी उत्पादन क्षमता से काफी कम होगा। ऐसी सूरत में उसकी लागत भी बढ़ जायेगी। इस प्रकार जब तक बाजार का आपका भाग बढ़ता नहीं, तब तक आप घाटे में रहेंगे। उदारीकरण की नयी नीति के कारण इस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता कुछ उद्योगों में बढ़ गयी है। मसलन, पैट्रोकेमिकल्स, अभी एक उदीयमान उद्योग है। जिन लोगों ने समय पर इसमें भारी पूंजी-निवेश का निश्चय किया, उनके दो लक्ष्य साथ-साथ पूरे हुए। एक, सरकार ने स्वयं जायजा लिया है कि भावी वर्षों में पैट्रोकेमिकल्स की कितनी दरकार होगी। उसने अनुमानित उत्पाद से अधिक का लाइसेंस देने का भी विचार किया। किंतु वह संभावित मांग से तीन-चार-पांच गुना अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे लाइसेंस चुने हुए राजनीतिक प्रभाववाले व्यावसायिक घरानों को ही दिये जायेंगे।

धीरूभाई अंबानी ने यह तथ्य समझ लिया था, क्योंकि वह कुशल व्यवसायी हैं, किंतु श्रीराम ने इसे नहीं समझा था। रामप्रसाद गोयनका ने तो धीरूभाई अंबानी के पहले ही यह सचाई जान ली थी। उन्होंने १०-१५ साल पहले प० बंगाल सरकार से हल्दिया पैट्रोकेमिकल्स नामक कारखाना शुरू करने का एक समझौता कर लिया था।

इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप्स ने इलेक्ट्रानिक्स के बढ़ते बाजार को पहचान लिया था। उसने कलकत्ता के पास साल्ट लेक नगर में ४० करोड़ रुपए मूल्य की भूमि का एक काम्पलेक्स रियायती दर पर खरीदा। प० बंगाल सरकार से उसे अन्य रियायतें व सहयोग भी प्राप्त हुए। फिलिप्स और गोयनका के व्यवसाय के भलीभांति फलने-फूलने की संभावना है। किंतु श्रीराम ऐसी कोई सुनियोजित परियोजना बनाने में विफल रहे हैं, जिसका बाजार विशिष्ट एकाधिकार सहित कायम हो और जिसके मूल्य के साथ-साथ मुनाफे भी ऊंचे हों।

इस प्रकार भारत के व्यावसायिक विस्तार का स्वरूप अब पहले से कहीं अधिक बदल गया है। यह अब मात्र ५०-६० या १०० जमे-जमाये घरानों की इजारेदारी नहीं रह गयीं है। इस क्षेत्र में अब नये घरानों का प्रवेश हो रहा है। साथ ही विदेशों के उनके सम्पर्क भी बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। इन सब कारणों से सरकार के लिए रास्ता आसान हो गया है कि वह सक्षम और संबंध-संपर्कों में माहिर लोगों को पूंजी-निवेश के लिए प्रोत्साहित करे।

अभी तक श्रीराम टाटा, बिड़ला, थापर, सिंघानियां, गोयनका और यहां तक कि कुछ समय पूर्व तक के खस्ताहाल मोदी से कुशलता और सक्षमता में पिछड़े हुए हैं, इसलिए श्रीराम के लिए अपना पुराना गौरव दुबारा हासिल करना इतना आसान नहीं है।

—कुमारेश चक्रवर्ती

ये रहे दो ख़ास कारण जिनकी वजह से मनाली वेंगसरकर ने विजिल साबुन अपनाया.

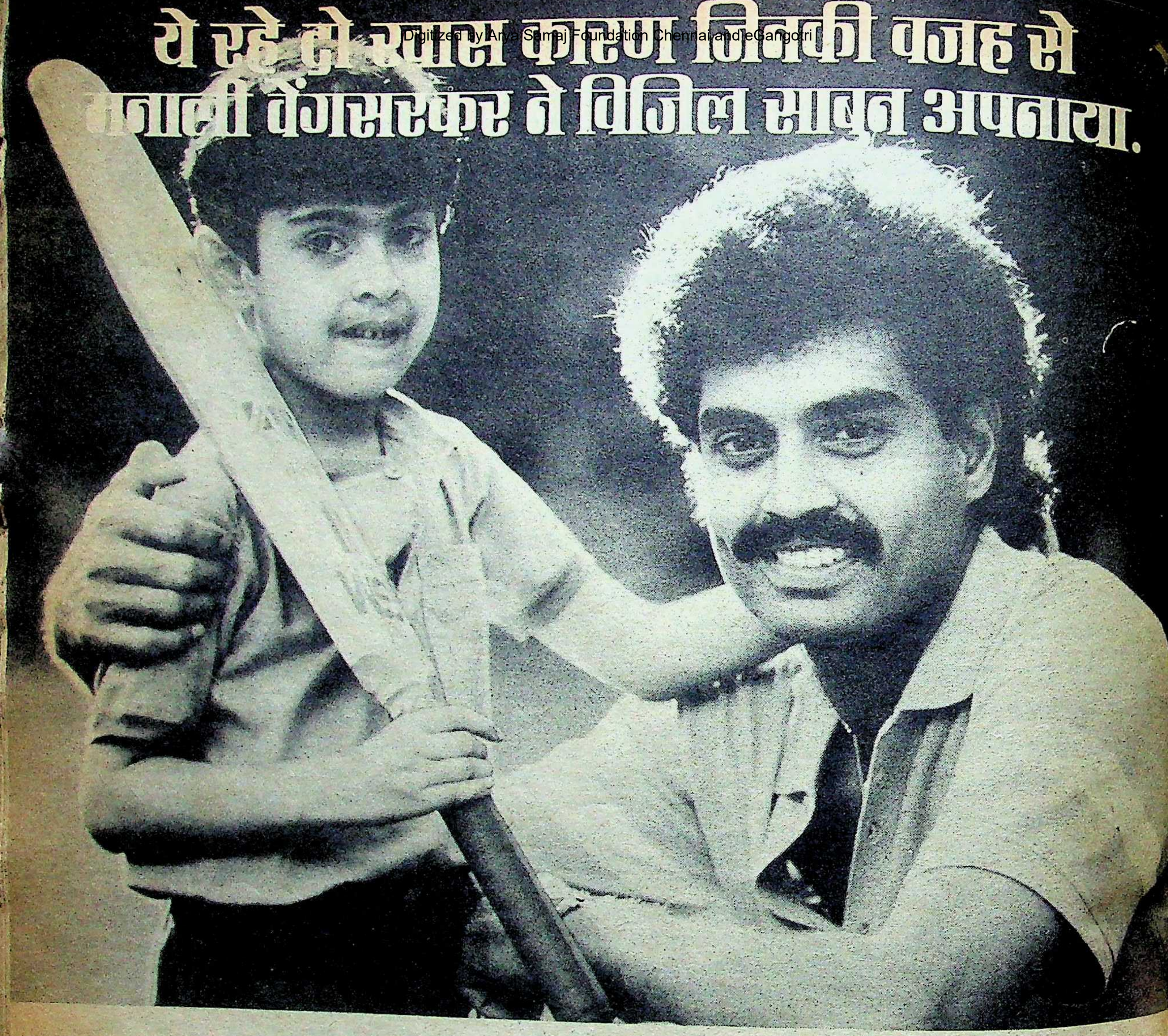

अपने परिवार की तंदुरुस्ती की हिफ़ाज़त कीजिए.
गोदरेज का नया साबुन विजिल ले आइए.

"दिलीप और अपने लाडले नकुल के आसपास ही तो मेरी दुनिया है", कहती हैं मनाली वेंगसरकर. "और चूंकि मेरी तरह आपके लिए भी अपने परिवार की तंदुरुस्ती ही सब कुछ है, आप हर चीज़ सोच-समझकर ही अपनाना चाहेंगी, चाहे नहाने का साबुन ही क्यों न हो.

इसीलिए तो मैंने विजिल साबुन ही चुना. विजिल में कुदरती तेल हैं जो त्वचा और तंदुरुस्ती की रक्षा करनेवाली अपनी खूबियों के लिए सदियों से मशहूर हैं. यह नरम मखमली झाग देता है. और इसकी खुशबू के तो बस क्या कहने! बेशक, मेरे परिवार की तंदुरुस्ती के लिए विजिल ही एकमात्र भरोसे का साबुन है."

Godrej
VIGIL
THE FAMILY HEALTH SOAP

विजिल-गोदरेज का नया साबुन
परिवार की तंदुरुस्ती का रखवाला.

गोदरेज

चढ़ी जवानी बुड्ढे नूं

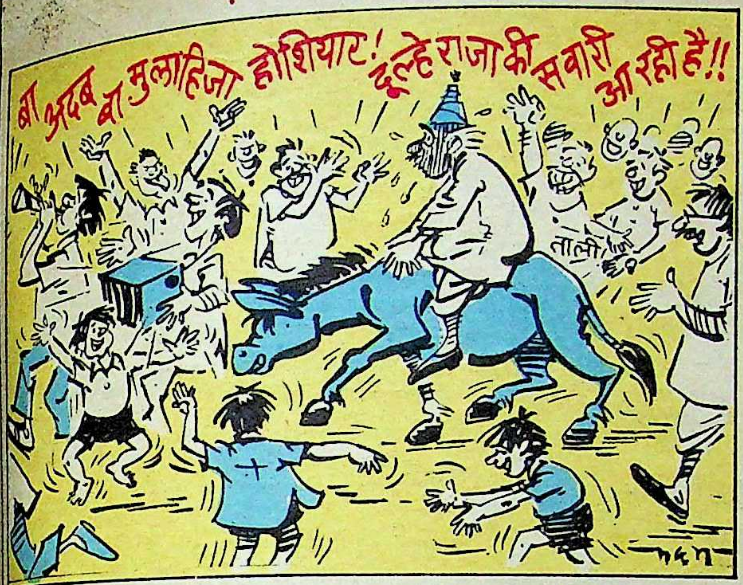
बा अदब बा मुलाहिज़ा होशियार! दूल्हे राजा की सवारी आ रही है!!
ताली
काक

जहां यह कहा जाता है कि साठ साल में मर्द सठिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी मानते हैं कि साठे पर ही तो मर्द पाठा होता है। यानी असली जवानी मर्द पर साठवें साल में चढ़ती है। अखबारों में किसी लंपट ससुर द्वारा बहू के साथ मुंह काला करने की खबरें अकसर साया होती रहती हैं, लेकिन किसी बुड्ढे पर इस कदर जवानी का जोश चढ जायेगा कि वह एक अबोध बालिका से शादी रचाने के लिए मय बारात कूच कर जायेगा, जानकर आश्चर्य होता है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कथवटियां गांव में एक ऐसा ही आश्चर्य हुआ है।

हुआ यों कि हवस का शिकार एक अमीर खूसट बुड्ढा १४ वर्षीय लड़की से शादी रचाने के लिए बारात लेकर आ धमका, लेकिन भला हो गांववालों का कि उनके बीच-बचाव से शादी तो थम ही गयी, उलटे उस छलिया बुड्ढे के मुंह में कालिख पोतकर गांववालों ने एक गधे पर बिठाकर गांव भर घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

मधुबालाओं की नंगई

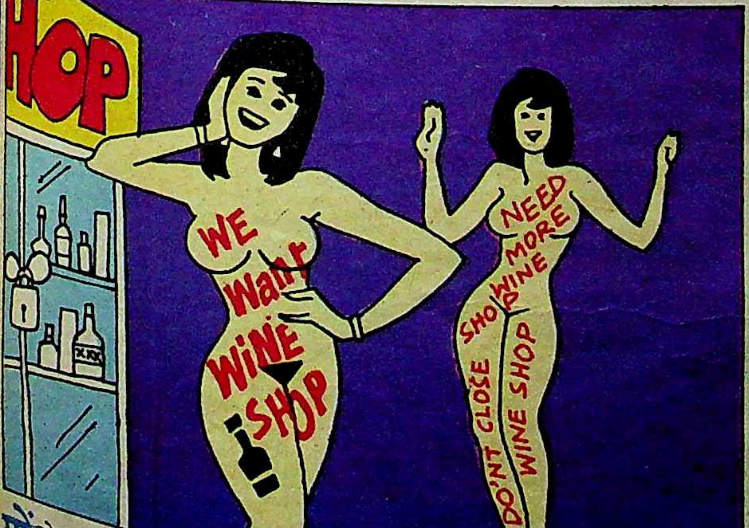

यों तो शराब और शबाब का रिश्ता पुराना है, लेकिन दोनों इस कदर मिल जायेंगे कि किसी सरकार के लिए परेशानी पैदा कर देंगे, समझ से परे है। लेकिन फिलीपींस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से फिलीपींस सरकार अपने देश की सारी मधुशालाओं को बंद करने का विचार कर रही है, तब से वहां की हजारों मधुबालाएं नग्न प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गयी हैं। दरअसल, ये शराब घर चूंकि कुकर्मों और अपराधों के केंद्र बनते जा रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन वहां की मधुबालाएं मानें तब न! ये बालाएं इतनी बौखलायी हुई हैं कि तकरीबन ६० हजार से अधिक नग्न प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये बेहयायी पर इस कदर उतारू हैं कि सरकार विरोधी नारे तख्तियों पर न लिखकर अपने नग्न शरीर पर लिखने को तैयार हैं। अब देखना है कि फिलीपींस सरकार इनके आगे झुकती है या ये बालाएं सरकार के आगे।

कटखना नकलची

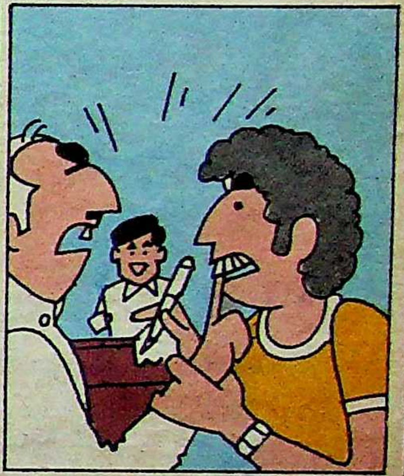

आजकल न तो नकल करना-कराना बुरा माना जाता है और न कक्ष-निरीक्षकों और परीक्षकों को चाकू-कट्टे दिखाना तथा पटाना। कक्ष-निरीक्षक के काम के डर के मारे कई लोग तो परीक्षा के दौरान किसी-न-किसी बहाने छुट्टी ही ले लेते हैं। लेकिन जो दुनियादारी में यकीन करते हैं, वे लाखों में खेल भी रहे हैं।

कोई नकलची परीक्षा भवन में चाकू-कट्टा दिखाने के बजाय किसी कक्ष-निरीक्षक की उंगली ही चबा डाले, तो आश्चर्य तो होगा ही। नागपुर विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी ही घटना घटी। हुआ यह कि देश के भावी कर्णधार वासुदेव खेतकर एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन पुर्जी के सहारे। इतने में ही कक्ष-निरीक्षक ने उन्हें धर-दबोचा। खेतकर ने न आव देखा, न ताव, कक्ष-निरीक्षक महोदय की उंगली पकड़ ली। वह बेचारे इधर-उधर भी न कर पाये कि खेतकर ने उनकी उंगली चबा डाली। शुक्र हुआ कि उनकी उंगली अलग होने से बच गयी।

पापी पेट के लिए

कहने को तो हमारे देश की सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं, अनेक कार्यक्रम भी चालू हैं, लेकिन सचाई कुछ और ही नजर आती है।आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जहां लोग दो जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कितनी ही माताएं अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेच रही हैं, तो कितने ही पति अब अपनी पत्नियों को अमीरों और साहूकारों के हाथों गिरवी रख रहे हैं। ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं, हमारे ही देश के प्रांत उड़ीसा के गंजाम जिले में घट रही हैं। गंजाम जिले के 'उसका' क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक राघव परीदा ने मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक से इस प्रकार की शिकायतें भी की हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के पास गरीबों के लिए इतना समय कहां कि वह उनकी सुध ले सकें।

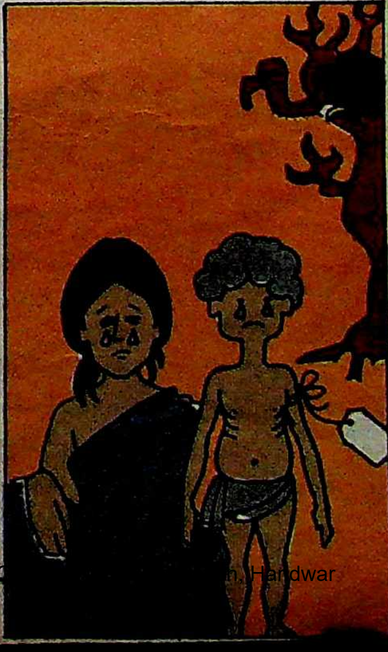

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

CC-0. In Public Domain. Haridwar.

फिलिस्तीनी समस्या है क्या ?

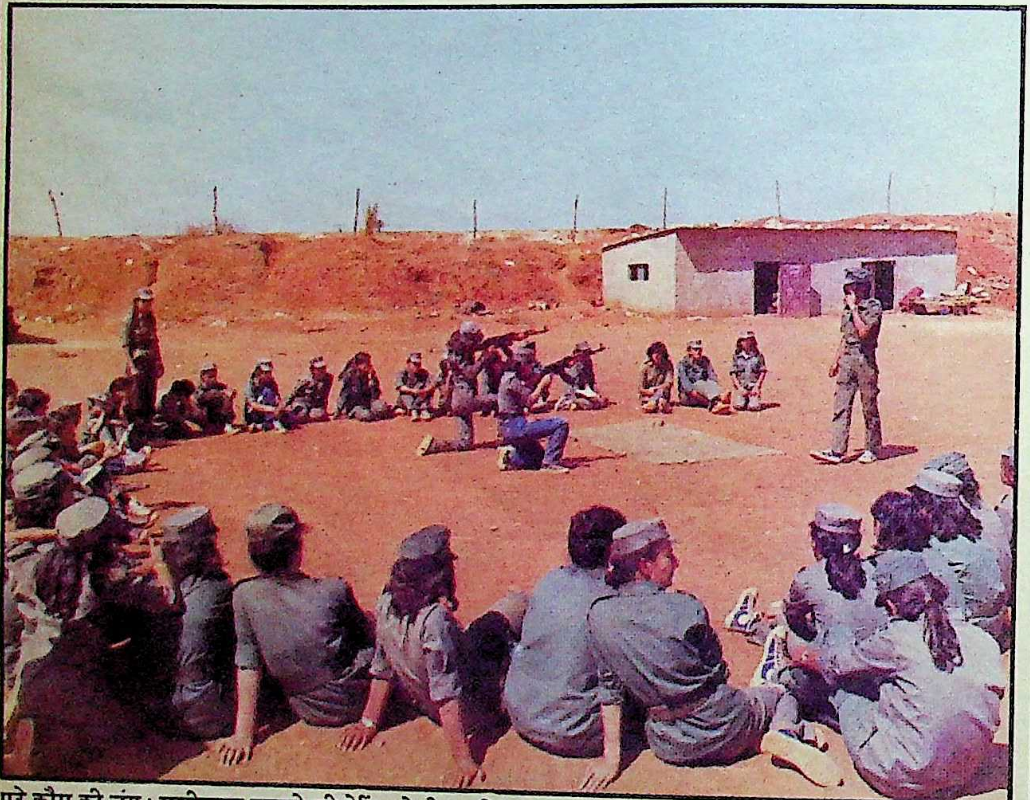

पूरे कौम की जंग : मशीनगन चलाने की ट्रेनिंग लेती लड़कियां

फिलिस्तीन को इस्रायल के कब्जे से मुक्त कराने के लिए पिछले चालीस सालों से फिलिस्तीनियों और इस्रायल के बीच ऐसी जंग चल रही है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। पांच बड़े युद्धों के अतिरिक्त झड़पें निरंतर जारी हैं और घात लगाकर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रमुख लोगों की नृशंस हत्याएं भी कर रहे हैं। लाखों यहूदी-अरबों की बलि इस संघर्ष में चढ़ चुकी है। कुछ प्रेक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि 'फिलिस्तीनी समस्या' से ही निकली कोई चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकती है। आखिर यह 'फिलिस्तीनी समस्या' है क्या और यह लाइलाज क्यों बन गयी है ? :

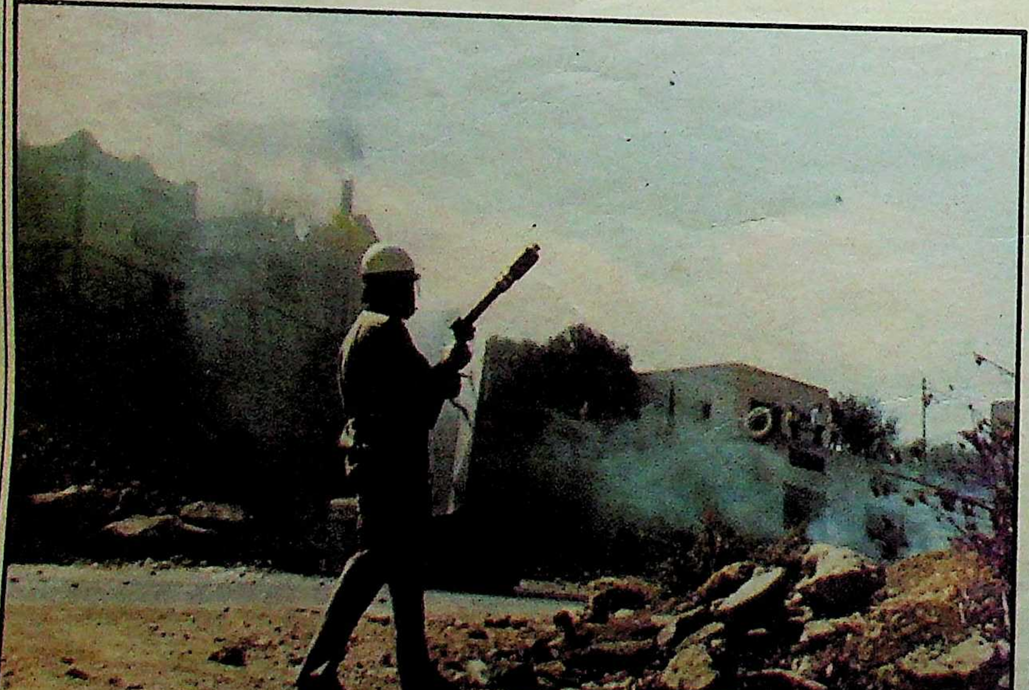

अंतहीन : इस्रायली सैनिक फिलिस्तीनी लड़ाकुओं पर गोली चलाते हुए

मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व : यासिर अराफात

"विदेशी यहूदियों का फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कोई हक नहीं बनता। यदि हम यह तर्क दें कि चूंकि कोई दो हजार वर्ष पूर्व यहूदियों के पूर्वज वहां बसे थे, इसलिए वह क्षेत्र यहूदियों का हो गया, तो दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो समान तर्क पर अपने अधिकारों का दावा करने लगेंगे। इससे विश्व में अस्थिरता और हिंसा का जो दौर आरंभ होगा, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है।"

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इन वाक्यों में समूची फिलिस्तीनी समस्या का सार मिल जाता है। इस्रायल ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को कब्जे में इसलिए रखा है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ 'बाइबल' के अनुसार उनके पूर्वज तकरीबन २००० वर्षों पूर्व वहां बसे थे। परंतु फिलिस्तीनियों का कहना है कि वहां पर लगभग तेरह सौ साल तक अरबों अथवा तुर्कों ने राज्य किया था। यदि ऐतिहासिक शासनकाल को ही मापदंड बनाया जाये, तो फिलिस्तीनियों का हक और मजबूत हो जाता है। इसी कारण से फिलिस्तीनी जनता इस्रायल को मान्यता तक नहीं दे रही है।

वैसे तो अपने राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते फिलिस्तीनी पिछले चालीस वर्षों से इस्रायल से जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले दिसंबर से चल रहा विद्रोह अपने आप में कई कारणों से अभूतपूर्व है। पहली बार, फिलिस्तीनियों का समूचा—चाहे वह किसान हो अथवा बुद्धिजीवी—इस विद्रोह में खुलकर भाग ले रहा है। अरब बहुमत क्षेत्रों में, जिन पर इस्रायल का कब्जा है, एक प्रकार का असहयोग आंदोलन चल रहा है। दुकानदार इस्रायली वस्तुएं बेचने से इनकार कर रहे हैं; कुछ घंटों के लिए दुकानें खोली जाती हैं और जब फिलिस्तीनी समर्थक खरीदारी कर चुके होते हैं, तो बंद कर दी जाती हैं। हर वर्ग का फिलिस्तीनी इस विद्रोह में निडर हो कर भाग ले रहा है। पहली बार यह लग रहा है कि फिलिस्तीनी आंदोलन ने इस्रायली प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यह विद्रोह अभी तक पुराने जोर-शोर से जारी है। वक्त बीतने के साथ उसके जोश में कोई कमी नहीं आयी है।

इस विद्रोह के दमन के लिए इस्रायल ने पूरा बल लगा दिया है। विद्रोहियों के साथ सख्ती तो बरती ही, उसके 'कमांडो बल' ने विद्रोह के सूत्रधार तथा फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के निकट सहयोगी अबू जिहाद की हत्या कर दी। इस हत्या से विद्रोह को झटका अवश्य लगा, लेकिन उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आयी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: आखिर यह समस्या

बुलंद हिम्मत: खच्चर पर प्रक्षेपास्त्र और अन्य हथियारें ले जाते हुए फिलिस्तीनी

रोजमर्रा की दिनचर्या: जंगक्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर जाते लोग

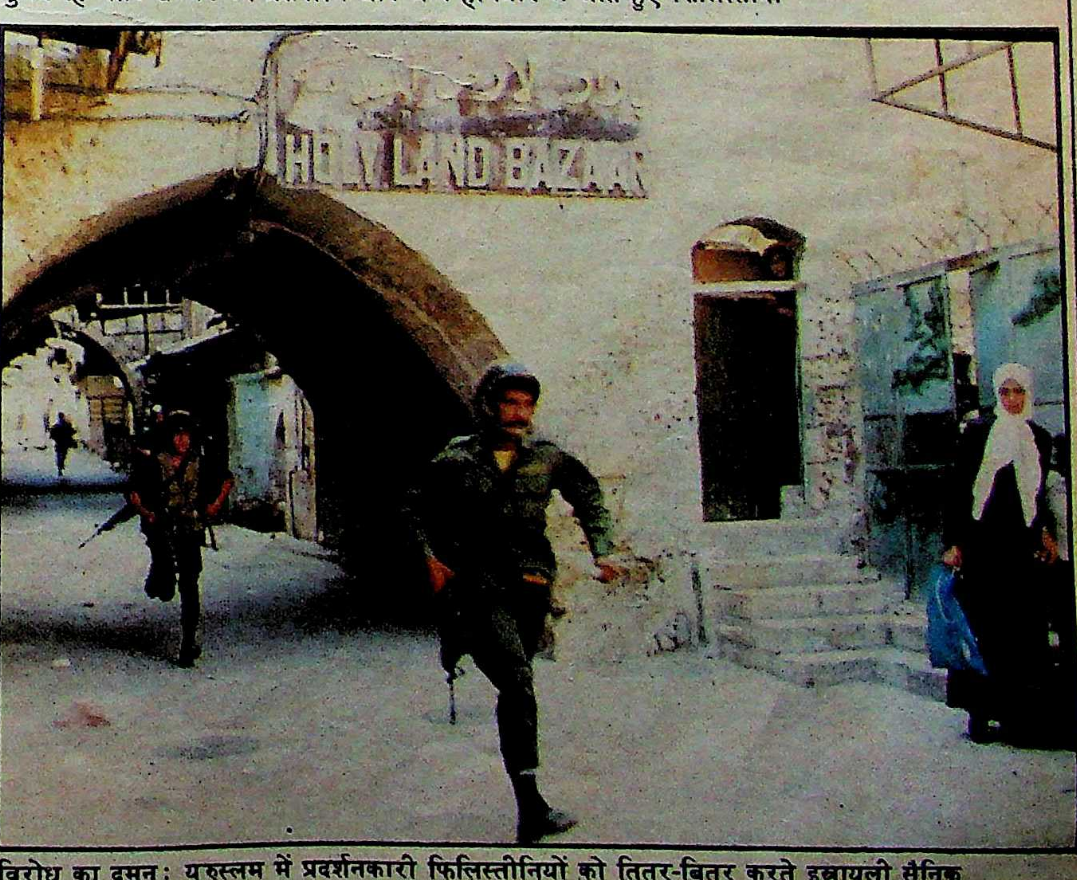

विरोध का दमन: यरुशलम में प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों को तितर-बितर करते इस्रायली सैनिक

सोने सा खरा स्वाद जिसका न कोई जवाब
२५ पैसे प्रति सिगरेट
कैवंडर्स गोल्ड लीफ
Cavanders Gold Leaf
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Cavanders GOLD LEAF
वैधानिक चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

कब, क्यों और कैसे उठी और इतने प्रयत्नों के बावजूद भी इसका कोई हल क्यों नहीं निकल पाया है? इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन यदि हम इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो समस्या की जड़ पा सकते हैं।

आज का इस्रायल ८००० ई०पू० के पहले फिलिस्तीन नामक राज्य का एक अंश था। इस्रायल के अलावा, फिलिस्तीन में जार्डन तथा मिस्र के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यह फिलिस्तीन भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ था। इस क्षेत्र पर मुसलमान (फिलिस्तीनी) और यहूदी, धार्मिक आधार पर हक जताते रहे हैं। मुसलमान इसलिए, क्योंकि उनकी मान्यता है कि वहां (यरुशलम) से उनके पैगंबर मोहम्मद सीधे जन्नत को गये थे और यहूदी अपना हक इसलिए जताते हैं, क्योंकि पवित्र ग्रंथ 'बाइबल' के अनुसार प्रभु ने वह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया था। जो भी हो, उस वक्त से ही यहूदी और फिलिस्तीनी समुदाय एक साथ इसी आशा से रहते आये हैं कि किसी दिन वह क्षेत्र उन्हें मिल जायेगा। विडंबना की बात तो यह है कि परंपरानुसार, अब्राहम नाम के व्यक्ति को यहूदियों और अरबों, दोनों का पूर्वज माना जाता है। कहा जाता है कि अब्राहम मेसोपोटेमिया के उर शहर से केनान आ बसे थे। मेसोपोटेमिया पश्चिमी एशिया का एक प्राचीन राज्य था और केनान फिलिस्तीन का दूसरा नाम ।

१००० ई०पू० में डेविड नाम के राजा ने फिलिस्तीन में बसे यहूदियों को एकत्र कर इस्रायल नामक राज्य की स्थापना की। इस राज्य ने डेविड के बेटे सोलोमन के राज्यकाल में अभूतपूर्व तरक्की की। सोलोमन के काल में यरुशलम के मोरियाह क्षेत्र में विश्वप्रसिद्ध मंदिर बना। परंतु सोलोमन की मौत के पश्चात राज्य के दो टुकड़े हो गये—इस्रायल और जुडाह। 'पवित्र स्थल' यरुशलम जुडाह की राजधानी बनी।

इसके बाद दोनों राज्यों को बाहरी हमलों से भारी नुकसान हुआ। ७२० ई०पू० के आसपास असीरियाई हमलावरों ने राज्य को तहस-नहस कर दिया और उसके वासियों को बंधक बनाकर ले गये। ये असीरियाई पश्चिम एशिया में बसे उस प्राचीन राज्य असीरिया के थे, जिसे फारसी शासकों ने बाद में हड़प लिया। लगभग १२० वर्षों पश्चात जुडाह पर भी हमला हुआ। बेबिलोन के शासक, नेबुकडनेजर ने यरुशलम और बाद में सोलोमन के काल में निर्मित मंदिर का नाश कर दिया। जुडाह में बसे यहूदियों को बंधक बनाकर बेबिलोन ले जाया गया। इस घटना के पचास वर्ष बाद फारसी शासक साइरस ने बेबिलोन को जीतकर यहूदियों को वापस लौटने का अवसर प्रदान किया। बेबिलोन उर की तरह भूमध्य सागर पर बसा एक प्राचीन शहर था।

इसी तरह से दोनों राज्यों में, जिन्हें संयुक्त रूप से फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता रहा है, उथल-पुथल होती रही। अंतत: ६३८ ई० में खलीफा ओमर ने यरुशलम पर कब्जा करके इस्लामी शासन की बुनियाद रखी। अगले ४५० वर्षों तक फिलिस्तीन में इस्लामी शासन रहा। इसके बाद लगभग एक शतक तक ईसाई 'क्रूसेडर्स' (जेहादियों) ने शासन किया। 'क्रूसेडर्स' उस गुट का नाम था, जिसकी स्थापना यरुशलम को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने के लिए की गयी थी। इन्होंने ११-१३ शताब्दी के मध्य पांच प्रमुख अभियान छेड़े, परंतु सभी असफल रहे। ईसाई शासन के अंत के बाद फिर अरब मुसलमानों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और अगले ८ सौ वर्षों तक उस पर राज्य करते रहे। १५१७ ई में ओटोमैन तुर्कों ने फिलिस्तीन को अपने राज्य में मिला लिया। तुर्कों के इस राज्य की स्थापना ओस्मान (प्रथम) ने १३वीं शताब्दी में की थी। आधुनिक तुर्की उस प्राचीन राज्य का एक अंग मात्र था। तुर्की शासन प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१९१८) तक बरकरार रहा। १९७१ में ब्रिटेन की फौज ने फिलिस्तीन पर आधिपत्य जमा लिया। उस वक्त फिलिस्तीन में दस प्रतिशत से भी कम संख्या में यहूदी और ईसाई थे तथा ८० प्रतिशत मुसलमान थे।

भारत पर भरोसा: यासर अराफात के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भूटान नरेश जिग्मे सिग्मे वांग्चुक

नया अध्याय: इस प्रकार, प्राचीन इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि फिलिस्तीन में हमेशा से अरब मुसलमानों का प्रभाव रहा है और उनकी संस्कृति फिलिस्तीन का एक अभिन्न अंग है। फिलिस्तीन में ब्रिटेन के प्रवेश से एक नये अध्याय का आरंभ हुआ। देखा जाये, तो ब्रिटेन द्वारा उस वक्त मंढ़ी गयी नीतियां ही वर्तमान फिलिस्तीनी समस्या का तात्कालिक कारण हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटेन इच्छुक था कि अरब गुट जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में उसकी सहायता करे। कुछ प्रमुख नेता जो ओटोमैन तुर्कों से छुटकारा पाना चाहते थे, ब्रिटेन की मदद करने के लिए सहमत हो गये। यह तय हुआ कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में ब्रिटेन अरब गुट की मदद करेगा। लेकिन, जहां एक ओर ब्रिटेन अरब मुसलमानों से इस तरह के वायदे कर रहा था, वहीं यहूदियों को उसने आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन में ही उन्हें एक राष्ट्र दिया जायेगा। ऐसे परस्पर-विरोधी वायदे करके ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी असंतुष्ट की नींव रखी। उसका झुकाव यहूदियों की तरफ था, यह बात खुलकर तब सामने आयी, जब ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री, लार्ड बैलफूर ने यहूदियों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को नवंबर १९१७ में एक खत लिखकर फिलिस्तीनी क्षेत्र में अलग राष्ट्र की स्थापना का अनुमोदन किया। यह पत्र 'बैलफूर घोषणा-पत्र' के नाम से जाना जाता है। अरबों तथा कुछ यहूदियों ने घोषणा को अव्यावहारिक कह कर उसकी निंदा की। परंतु ब्रिटेन टस-से-मस नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीनी समस्या का समाधान ढूंढ़ने के बजाय उसने उसे जटिल कर दिया।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात ब्रिटेम और फ्रांस सशक्त राष्ट्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद का बोलबाला तो था ही, लिहाजा यह तय किया गया कि पश्चिम एशिया के क्षेत्रों को इन दोनों महाशक्तियों के अधिकार में तब तक रखा जाये, जब तक इस क्षेत्र के राज्य स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासन चलाने में सक्षम न हो जायें। इस दौरान उन्हें महाशक्तियों से आर्थिक और प्रशासनिक सहायता मिलती रहेगी। यह फैसला राष्ट्र-संघ (लीग आफ नेशंस) ने किया। लीग 'राष्ट्र-संघ' की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के शांति और स्थिरता कायम करने के उद्देश्य से की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में था। परंतु १९४६ में यह संस्था भंग कर दी गयी और उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।

उक्त व्यवस्था पर २४ जुलाई, १९२२ में हस्ताक्षर हुए और २२ सितंबर को यह लागू होगयी। इसके तहत फिलिस्तीन और तत्कालीन जार्डन ब्रिटेन के अधिकार में आ गये तथा सीरिया और लेबनान फ्रांसीसी अधिकार में। लेकिन, जहां सीरिया को १९४४ में, लेबनान को १९४३ में और जार्डन को १९४६ में स्वतंत्रता मिल गयी, फिलिस्तीन का कोई फैसला नहीं हुआ और वह संघर्ष का मैदान बना रहा।

बढ़ते यहूदी, घटते अरबी : प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद विश्व के अन्य हिस्सों में बसे यहूदियों को फिलिस्तीनी में आकर बसने को उत्साहित किया गया। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे वहां अरब मुसलमानों की संख्या घटती गयी और यहूदियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। १९१८ में यहूदियों की संख्या मात्र ५६,००० थी, वहीं १९३९ में यह बढ़कर ४४५,००० हो गयी। इस वृद्धि का एक कारण जर्मन के शासक हिटलर द्वारा यहूदियों का उत्पीड़न था। उन दिनों भारी संख्या में यहूदी पूर्वी यूरोप में बसे थे, लेकिन हिटलर के दमन के कारण वे फिलिस्तीन अथवा अमरीका में भाग खड़े हुए।

जैसे-जैसे यहूदियों की संख्या बढ़ती गयी, वैसे-वैसे उन्होंने फिलिस्तीन में जमीन भी हथियानी आरंभ कर दी। १९१९ में फिलिस्तीनी भूमि का कुल २.५ प्रतिशत हिस्सा उनके अधिकार में था और १९३९ तक यह बढ़कर ५.७ प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से आहिस्ता-आहिस्ता यहूदी फिलिस्तीन के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करते गये।

ब्रिटेन के कानों में फिलिस्तीनी अरबों में बढ़ते असंतोष की बातें पहुंचने लगीं। १९३९ मेंब्रिटेन सरकार ने इस असंतोष पर एक रपट तैयार करने के लिए लार्ड पील की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। लार्ड पील ने अपनी रपट में कहा कि फिलीस्तीन को जबरन एक यहूदी राष्ट्र बनाना ही सारी समस्या की जड़ है। लार्ड पील ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की विरोधाभासी नीतियों ने फिलिस्तीनी समस्या को जटिल बना दिया है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उंन्होंने फिलिस्तीन के बंटवारे की सलाह दी—एक हिस्सा फिलिस्तीनी अरब, तो दूसरा यहूदियों का राष्ट्र। दोनों ही समुदायों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहूदियों का कहना था कि यह प्रस्ताव 'बैलफूर घोषणा पत्र' के विरुद्ध है, जबकि फिलिस्तीनी अरब अपने राष्ट्र का बंटवारा किसी कीमत पर नहीं चाहते थे। तब ब्रिटेन ने एक और प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार १९४९ से दोनों-यहूदी और अरब-सत्ता की बागडोर मिल-बांटकर चला सकते थे। इस प्रस्ताव को यहूदियों ने तुरंत ठुकरा दिया और १९४२ में फिलिस्तान में अपने राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी। यह उथल-पुथल द्वितीय विश्व युद्ध (१९३९-४५) तक चलती रही। आये दिन फिलिस्तीन में दंगे होने लगे। फिलिस्तीनी अरब और यहूदियों के मध्य डटकर लड़ाइयां होने लगीं।

इस्रायल की स्थापना : एक ओर फिलिस्तीन में हिंसा बढ़ती गयी, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के आधिपत्य की समाप्ति की अवधि भी निकट आने लगी। मई १९४८ में फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिलनी थी। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से यह तय हुआ कि फिलिस्तीन का बंटवारा ही समस्या का एक मात्र समाधान है। यहूदियों को इस बंटवारे में उतना हिस्सा नहीं मिल रहा था, जितने की उन्हें आशा थी। परंतु वह संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें फिलिस्तीन में अपना राष्ट्र बनने के आसार नजर आने लगे थे। अरबों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव को लेकर बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे और यह निश्चित हो गया कि बंटवारे से इस समस्या का हल होना तो दूर, हालात और भी गंभीर होते जायेंगे। और हुआ भी यही। १५ मई, १९४८ को हिंसात्मक प्रदर्शनों के बीच इस्रायल राष्ट्र की स्थापना हुई।

इस स्थापना के बाद से लेकर पांच बड़े अरब-इस्रायल युद्ध हुए हैं। पहला तो स्थापना के तुरंत बाद १९४८ में ही हुआ। मिस्र, सीरिया, जार्डन, लेबनान तथा इराक की सेनाओं ने इस्राइल पर धावा बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध-विराम की घोषणा हुई, लेकिन समस्या बनी-की-बनी रही। जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण किया, तो इसके विरोध में १९५६ में इस्रायल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर उस पर हमला किया। यहां भी संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमरीका और सोवियत के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त किया गया। ६० कि लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है और यूरोप तथा एशिया के बीच का सब सीधा समुद्री रास्ता है। इसका निर्माण १८५ १९६९ के दौरान हुआ। १८७५ में इस पर ब्रिटेन अधिकार जमा लिया था। बाद में यह मिस्र के अधीन आ गयी जिसने १९५६ में इसका राष्ट्रीकरण कर दिया। १९४८-१९७५ के मध्य इसे इस्रायली पोतों के लिए बंद कर दिया। इससे इस्रायल का यूरोपीय देशों से व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा।

पांचों युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण १९६७ का युद्ध माना जाता है जो छह दिनों तक चला। इसमें इस्रायल ने मिस्र के हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि सारे अरब गुट के लिए वह हार शर्मनाक बन गयी।

१९७३-७४ में फिर से मिस्र, सीरिया और इराक ने एक जुट होकर इस्रायल पर धावा बोल

साक्षात्कार/**खालिद अल शेख**

अमरीका को छोड़कर सारा विश्व हमारे साथ है

खालिद अल शेख भारत में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि हैं। दिल्ली के विशिष्ट रिहायशी इलाके वसंत विहार में स्थित पीएलओ मुख्यालय बाहर से किसी सामान्य रिहायशी घर से कुछ भिन्न नहीं दिखता। भीतर भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। वहां प्रवेश करने वाले के बारे में जो जानकारी उन्हें चाहिए उसे वे पूर्व भले ही ले लेते हों पर वहां जाने पर कोई सुरक्षा जांच से गुजरना नहीं पड़ता। इस मुद्दे को जब खालिद अल शेख के सामने उठाया गया तो उनका उत्तर था हम शत्रु में नहीं, मित्र देश में हैं। वैसे भी हमारा रवैया किसी देश में अपनी सेना तैनात करने का नहीं है। १९४२ में जन्मे खालिद अल शेख की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा फिलिस्तीनी विश्वविद्यालय में हुई। अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री उन्होंने बेरूत विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। कुछ समय मुक्ति सेनानी के रूप में काम करने के पश्चात वह १९७० से राजनयिक सेवा में हैं। भारत में उन नियुक्ति फरवरी १९८४ में हुई। उन अनुसार यह कार्यकाल सामान्यतः चार वर्ष का होता है। भारत में बिताये वर्ष के अपने कार्यकाल को उन्होंने अनुभवकोश में पर्याप्त वृद्धि करार दिया है। इससे पहले वह रूमानिया, पाकिस्तान और अफ्रीका के केन्या व यूगांडा में कार्यरस्त कर चुके हैं। 'माया' ने फिलिस्तीनी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर उनसे विस्तार बातचीत की है। उनकी मान्यता है किसी भी समस्या के हल के लिए आवश्यक है और एक दिन हम फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना करने सफल होंगे। यहां प्रस्तुत हैं, विभिन्न मुद्दों पर खालिद अल शेख के वि

दिया। इस बार इस्रायल युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जिससे उसे काफी क्षति हुई। यह युद्ध 'योम किप्पर युद्ध' के नाम से मशहूर है, क्योंकि जिस दिन अरब राष्ट्रों ने हमला किया था, वह यहूदियों की सात 'बड़ी छुट्टियों' में से एक छुट्टी—योम किप्पर का दिन था। इस दिन यहूदी अपने प्रभु से पिछले वर्ष किये गये पापों के लिए क्षमायाचना करते हैं और उपवास रखते हैं।

पांचवा युद्ध १९७८ में हुआ। फिलिस्तीनी छापामारों ने लेबनान में बसे अपने अड्डों से इस्रायल पर हवाई हमले किये। इसके जवाब में इस्रायली सैनिक लेबनान में घुस गये और घमासान युद्ध आरंभ हो गया। फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता काम आयी।

यासर अराफात का उभार : अरब गुट तो इस्रायल से जूझते ही रहे, उधर फिलिस्तीनी आंदोलन को सशक्त करने के लिए १९५८ में 'अल फतह' नाम के संगठन की स्थापना हुई। इसके नेता बने यासर अराफात। अनेक फिलिस्तीनी गुट उभरे, लेकिन 'अल फतह' इनमें प्रमुख रहा। इन गुटों ने यह महसूस किया कि अलग-अलग लड़कर वे इतने प्रभावशाली नहीं बन सकते थे, लिहाजा इन सभी को एकता के सूत्र में बांधा 'फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन' (पीएलओ) ने, जिसकी स्थापना १९६४ में हुई। पिछले २४ वर्षों में इस गुट ने इस्रायलियों के विरुद्ध जेहाद छेड़ रखा है।

जहां तक अरब गुट का सवाल था, उसका नेता निस्संदेह मिस्र था। वह इस्रायल से इसलिए चिढ़ा हुआ था, क्योंकि १९६७ में इस्रायली सैनिकों ने उसके सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। यह प्रायद्वीप स्वेज नहर में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। लेकिन १९७९ में इस्रायल से संधि के पश्चात उसकी साख अरब गुट में गिर गयी। उसे सिनाई वापस मिल गया, परंतु उसके हाथ से अरब गुट की बागडोर जाती रही।

१९६७ के युद्ध में इस्रायल ने मिस्र, सीरिया और जार्डन के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। मिस्र में गाज़ा पट्टी, सीरिया में गोलान पहाड़ी तथा जार्डन का पश्चिमी किनारा—इन क्षेत्रों में अरब मुसलमानों का बहुमत है—इस्रायल ने हथिया लिया। दरअसल, वर्तमान फिलिस्तीनी विद्रोह इन्हीं इस्रायली 'शासित प्रदेशों' में सबसे तीव्र रहा है।

गाजा क्षेत्र ३७० वर्ग किमी लंबी, भूमध्य सागर तट पर स्थित एक समतल पट्टी है, जहां इस्रायल से भागे मुसलमान शरणार्थियों का बहुमत है। यह क्षेत्र १९४८ से मिस्र का अंग रहा है, लेकिन अब इस्रायलियों के कब्जे में है। गोलान पहाड़ी सीरिया और लेबनान के मध्य स्थित पहाड़ी इलाका है। यहां से सीरियायी और लेबनानी सैनिकों ने इस्रायल पर १९६७ में हमले किये थे। उसी वर्ष इस्रायल ने गोलान को अपने कब्जे में कर लिया और १९८१ में अपने राष्ट्र का हिस्सा बना लिया। जार्डन में बहने वाली जार्डन नदी का पश्चिमी किनारा भी इस्रायल ने हथिया लिया है। इस किनारे पर बसे शहर हैं, हेब्रों, जेरीको, नाबलस तथा पुराना यरुशलम।

ये क्षेत्र फिलिस्तीनी विद्रोह के केंद्र बिन्दु रहे हैं। फिलिस्तीनियों की मांग है कि इस्रायल इन क्षेत्रों से हटे तथा फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होने दे। उधर इस्रायल इन इलाकों से कतई हटना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप भी असफल रहे हैं, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे को मान्यता नहीं देते। इस समस्या का समाधान, दोनों महाशक्तियां, अमरीका और सोवियत रूस, खोजने में लगी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि यहूदी अमरीका की राजनीतिक अथवा आर्थिक व्यवस्था पर छाये हुए हैं, अमरीका इस्रायल का समर्थक बन गया है। इस्रायल की ही तरह, वह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता नहीं देता है। क्योंकि मुक्ति संगठन फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र प्रतिनिधि है, इसलिए कोई भी समझौता-वार्ता उसकी अनुपस्थिति में निरर्थक है। यही कारण है कि अमरीकी विदेश मंत्री जार्ज शुल्ज का हाल का समझौता प्रस्ताव विफल रहा है। उधर सोवियत रूस ने फिलिस्तीनियों से व्यावहारिक रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें यहूदियों के राष्ट्र को तो मान्यता देनी ही होगी। हां, फिलिस्तीनियों को भी वह राष्ट्र मिलना चाहिए जो इस्रायलियों के कब्जे में है।

इस्रायल की दमन-नीतियों का विरोध अब अमरीका और खुद इस्रायल के भीतर भी होने लगा है। इस्रायल द्वारा अपना शांति प्रस्ताव ठुकराये जाने से शुल्ज काफी क्षुब्ध हैं। इस्रायल के एक प्रमुख शहर तेल अवीव के महापौर श्लोमो लाहेत ने तो इस्रायली सरकार से आग्रह किया है कि वह पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी पर से अपना अधिकार वापस ले और समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने में प्रयत्नशील हो जाये।

—राजेश सिंह

जिहाद की हत्या : अबू जिहाद की हत्या फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के लिए एक री क्षति है। उन्होंने न केवल गाजा पट्टी र पश्चिमी किनारे में पिछले छह महीनों से रहे फिलिस्तीनी विद्रोह का नेतृत्व किया, कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन में एकता ये रखने में भी एक अहम भूमिका निभायी । विश्व के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हाद की हत्या से दुख हुआ होगा।

हाद के मरणोपरांत फिलिस्तीनी मुक्ति ठन का सीरिया अथवा जार्डन से संबंध : हाद की अंत्येष्टि सीरिया की राजधानी, श्क में की गयी। देखा जाये तो एक प्रकार उनकी हत्या सीरिया और फिलिस्तीनी संगठन के मध्य समझौते की कड़ी बन । दोनों के बीच पिछले छह वर्षों से नावपूर्ण संबंध रहे हैं। (१९८२ में सीरिया राष्ट्रपति हफीज असद ने फिलिस्तीनी रवाइयों के विरोध में फिलिस्तीनी नेता र अराफात को देश से चले जाने के लिए हा था)। जहां तक जार्डन का प्रश्न है, ारा उनसे कोई गंभीर मतभेद नहीं रहा है। कुछ बातों पर—जैसे कि फिलिस्तीनीयों समस्या के हाल का तरीका और अमरीका रवैया—हम उनसे सहमत नहीं रहे हैं। तु ये मतभेद गंभीर नहीं कहे जा सकते। विषय में जार्डन के शाह के हाल के नों में समझदारी झलकती है। जिहाद की वह बड़ी इज्जत करते थे।

लस्तीनी मुक्ति संगठन में गुटबाजी : इस न की स्थापना १९६४ में हुई थी। पना से पूर्व ऐसे कई गुट थे जो लस्तीनियों को अपना हक दिलाने की र संघर्ष कर रहे थे। इनमें से एक था, फतह, जिसकी स्थापना १९५८ में हुई थी। लेकिन संगठन की स्थापना के पश्चात सभी गुट इसमें शामिल हो गये। इसलिए अंदरूनी मतभेद होना स्वाभाविक है। इसका यह मतलब नहीं है कि हममें एकता नहीं है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जैसा कि आपके देश भारत में है। हम अपने संगठन से विभिन्न गुटों की विचारधाराओं की कद्र करते हैं। और फिर, संगठन में कितने गुट हैं, महत्वहीन हैं। कोई भी फिलिस्तीनी यह नहीं कह सकता कि 'मैं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थक नहीं हूं।' चाहे वह किसी भी गुट का सदस्य हो, वह मुक्ति संगठन को अपना प्रतिनिधि मानता है। यह सवाल कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन हर फिलिस्तीनी का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, उसी प्रकार का है कि भारत सरकार हर भारतीय नागरिक की प्रतिनिधि है कि नहीं ? अमरीका और इस्राइल को छोड़कर विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी है।

फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन का भविष्य : हम हमेशा से यह मानते रहे हैं कि अंत में न्याय की जीत होती है। हमें विश्वास है कि एक दिन हम अपने राष्ट्र की स्थापना करने में सफल होंगे और अपनी इच्छा के मालिक होंगे। इस मुहिम में सारा विश्व हमारा साथ दे रहा है। किसी भी समस्या के हल के लिए शांति आवश्यक है। इस्राइल के उग्र रवैये से खुद यहूदियों को नुकसान होगा। वे भविष्य में शांतिपूर्वक नहीं रह पायेंगे। अभी चल रहे विद्रोह के पश्चात अमरीका में भी फिलिस्तीनियों को लेकर विचारों में आशापूर्ण परिवर्तन आये हैं। इस्रायलियों का प्रोपगेंडा भी विफल रहा है।

—रंजना कक्कड़

सिंहासन खाली है...

अपने विशाल माफिया साम्राज्य से हाजी मस्तान द्वारा संन्यास ले लेने के कारण माफिया डान (सरदार) के सिंहासन के लिए नव-माफिया सरदारों के बीच खूनी जंग जारी है। वरदराजन की मौत, आलम जेब, महेश ढोलकिया की हत्या तथा दाऊद की फरारी के कारण माफिया डान का जो सिंहासन खाली पड़ा है, उसका असली हकदार कौन है?

दाऊद का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: अरविंद ढोलकिया

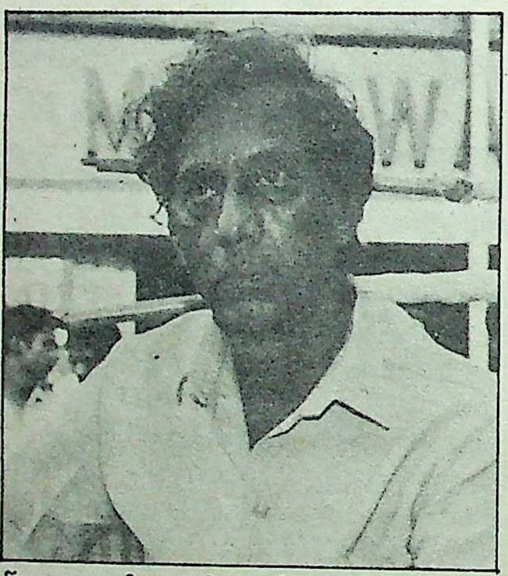

सिंहासन खाली कर गये: हाजी मस्तान

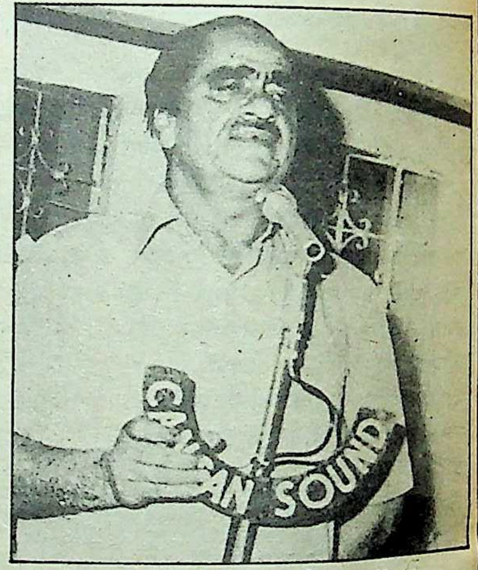

सुलह-सफायी की कोशिश: करीम लाला

१७ मई, १९८८ की रात सहार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक पुलिस तथा कस्टम अधिकारियों की आमदरफ्त तेज हो गयी। दुबई, बहरीन, कतार आदि खाड़ी के देशों से आनेवाली उड़ानों, विशेषकर कुवैत एयरलाइंस के विमान से उतरनेवाले हर यात्री पर न केवल कड़ी नजर रखी जा रही थी, बल्कि उनमें से हर एक से एक विशेष हुलियावाले यात्री के बारे में पूछतांछ की जा रही थी। पूरी रात तथा दूसरे दिन की सारी सरगर्मी अंततः निष्फल रही और जिस विशिष्ट 'अतिथि' की उन्हें दरकरार थी, वह बंबई नहीं पहुंचा।

यह विशिष्ट अतिथि था—दाऊद इब्राहीम, बंबई की अपराध दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया डान, जिसके खून के प्यासे एक तरफ दूसरे माफिया गिरोहों के डान थे, तो दूसरी तरफ हत्या, तस्करी आदि तमाम वारदातों के लिए पुलिस और कस्टम अधिकारियों को उसकी तलाश थी। पुलिस तथा कस्टम विभाग को सूचना मिली थी कि दाऊद अपने भाई नूरा उर्फ नूरुल हक इब्राहीम के साथ ईद मनाने तथा उसकी अनुपस्थिति के कारण बंबई में उत्पन्न हुए कई व्यावसायिक झगड़ों को निपटाने के लिए बंबई आनेवाला है। मई प्रथम सप्ताह में ही नूरा बंबई से दुबई दाऊद के पास चला गया था, क्योंकि १९८५-८६ में रहीम खान, समद खान फिर आलमजेब की हत्याओं के हादसे के बाद दाऊद के भारत से दुबई पलायन के कारण पुलिस उसके छोटे भाई अनीस इब्राहीम तथा दूसरे साथियों को परेशान कर रही थी। अनीस जब भी अपराध के एक मामले में जमानत पर छूटता, तो उसे तुरंत पुलिस दूसरे जुर्म में गिरफ्तार कर फिर जेल में डाल देती। इसके अलावा करीमलाला, ढोलकिया बंधु, शेट्टी गिरोहों के अतिरिक्त कई और गिरोहों के शातिर मुजरिम उसकी तलाश में थे कि उसकी हत्या कर वे उस खूनी जंग का एक अध्याय खतम कर दें, जिसे दाऊद ने शुरू किया था।

पुलिस तथा दुश्मनों के शिकंजे से बचने के लिए दाऊद ने बंबई से अस्थायी तौर पर अलविदा

कह कर दुबई में अपना अड्डा जमाया और वहां से पाकिस्तानी तस्कर हाजी अशरफ, अब्दुल्ला भट्टी, सैयद अहमद बावा मियां की सहायता से भारत में सोने व ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। लेकिन बीच-बीच में वह चोरी-छिपे अपने परिवार (अपनी कश्मीरी बीवी, बेटी, भाइयों) तथा गिरोह के लोगों से मिलनें के लिए बंबई आता रहता और हर बार पुलिस व कस्टम द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए बिछाये सारे जाल नाकामयाब हो जाते, जबकि बंबई में उसके आने की सूचना संबंधित लोगों को, उसकी विशिष्ट जीवन शैली के कारण बड़ी आसानी से मिल जाती। बंबई तथा दिल्ली पुलिस व बड़े अहलकारों के बीच अपनी ऊंची पहुंच के कारण वह कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सका, न ही दुबई सरकार ने उसे भारत सरकार को, भारतीय विदेश मंत्रालय के जनवरी १९८७ में क़िये गये निरंतर अनुरोधों के बावजूद, सौंपने की जरूरत समझी।

निकाह में : एक सूचना के अनुसार दाऊद ४ फ़रवरी, १९८७ को अपने छोटे भाई इब्राहीम के निकाह में शामिल होने के लिए बंबई, दिल्ली होते हुए आया। ७ फ़रवरी '८७ को बांद्रा कोर्ट के सामने स्थित एक तीन सितारा होटल के एक बंद कमरे में उसने एक वरिष्ठ पुलिस अफसर से गुफ्तगू की, जो इस इलाके का अफसर था।

दाऊद तथा उसके गिरोह के दूसरे फरार मुजरिमों के मामले में पुलिस की लापरवाही एवं निष्क्रियता के लिए खिंचाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज एचएस धारे ने कहा था, "कानून और व्यवस्था नकारा हो रही है और हत्यारे पुलिस की पकड़ से निर्द्वंद्व हो आजाद घूम रहे हैं।...सेशन जज की अदालत में मुकदमे के दौरान हत्यारों ने एक अभियुक्त की गोली मारकर हत्या कर दी, हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, फिर कैसे उसे कानून और हिरासत से भाग जाने दिया गया?" उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 'फौजदारी के मामले का अभियुक्त अदालत के सामने एक एडवोकेट की तरह वकालतनामे के साथ कैसे पेश हो सकता है?' उन्होंने दाऊद इब्राहीम की इस अपील को, कि अदालत में पेश होने पर उसके दुश्मन उसे मार सकते हैं, रद्द करते हुए पुलिस को तुरंत दाऊद तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी सलाह दी थी कि दाऊद का पता लगाने के लिए पुलिस प्रायवेट डिटेक्टिव एजेंसियों की सहायता ले, जैसाकि अमरीका में होता है। लेकिन इसके बावजूद, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक, पुलिस दुबई में रह रहे दाऊद पर हाथ नहीं डाल पायी। बंबई के अपराध जगत में अपना रौब गालिब करने के लिए लोग पहले मस्तान भाई का नाम लिया करते थे, लेकिन अब दाऊद भाई का नाम लेते हैं।

नहीं रहे: वरदराजन मुदालियार

बंबई लौटने का इंतजार: दाऊद इब्राहीम (बायें से तीसरा)

शुरुआत एक दूकान से: कमाठीपुरा की बदनाम गलियों में रहनेवाले सीआईडी हवलदार हक्सर इब्राहीम के दो किशोर बेटों—शाबिर तथा दाऊद इब्राहीम ने मनीष मार्केट में तस्करी के सामानों की एक छोटी-सी दूकान खोली। कमाठीपुरा में उनसे थोड़ी ही दूर रहनेवाले अमीरजादा और आलमजेब से, जो उन्हीं की तरह जुर्म की अंधेरी दुनिया में आये थे, उनकी दोस्ती हो गयी। कमाठीपुरा से कुछ ही फर्लांग दूर गिरगांव में रहनेवाले दो सिंधी बंधुओं-अरविंद तथा महेश ढोलकिया ने भी, पिता की मौत के बाद, रोजगार के रूप में तस्करी के कपड़े बेचने की एक छोटी-सी दूकान खोल ली। इन तीनों किशोर-बंधुओं ने तस्करी की छोटी-सी दुनिया से निकल कर अपने विभिन्न काले धंधों के बल पर चार-पांच वर्ष के भीतर ही संपन्नता तथा अपराध जगत में एक विशेष रुतबा हासिल कर लिया। यहीं से शुरुआत हुई उन तीनों अपराध-कुंवरों के बीच माफिया डान बनने की तथा एक दूसरे पर हावी होने की ललक।

दाऊद बंधुओं से मतभेद हो जाने के कारण अमीरजादा और आलमजेब ने जब उनसे नाता तोड़ कर समद खान से नाता जोड़ लिया, तो यह बात सबसे ज्यादा अखरी दाऊद इब्राहीम को। दाऊद ने भी जब दूसरों के लिए सुपारी लेकर काम करना शुरू किया, तो करीमलाला गिरोह ने इसे अपने एकछत्र साम्राज्य पर दाऊद बंधुओं का अतिक्रमण माना। समद खान अपने तीन घनिष्ठ सहयोगियों (अमीरजादा, आलमजेब खान तथा सईद बट्टा) के साथ मिल कर बंबई तथा बंबई से बाहर भी 'एसाइनमेंट' पर काम किया करता था। उसकी बढ़ती हुई ताकत के कारण उसे 'डोंगरी का बादशाह' ही नहीं हाजी मस्तान का, माफिया डान के रूप में नया विकल्प भी मान लिया गया। लेकिन अपने को असली विकल्प माननेवाले दाऊद का करीमलाला गिरोह से पहला टकराव १९७५ में मुसाफिर खाना को लेकर हुआ, जहां हज के लिए मक्का रवाना होने के पूर्व देश के कोने-कोने से बंबई पहुंचे मुस्लिम यात्री ठहरा करते थे। मुसाफिर खाना पर जब कुछ मुजरिम तबके के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उन्हें बेदखल करने का काम, मुसाफिर खाना के नये मालिक ने दाऊद गिरोह पर सौंपा। कब्जा जमाये पक्ष ने दाऊद से बचाने के लिए समद खान को सुपारी दी। पुलिस ने खबर मिलते ही मुसाफिर खाना क्षेत्र को घेर लिया, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी।

बुजुर्ग माफिया डानों (हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीमलाला आदि) की दखलंदाजी से मुसाफिर खाना में दोनों खूंख्वार गिरोंहों के बीच खूनी जंग होते-होते बच गयी, लेकिन समद खान के गिरोह द्वारा उर्दू अखबार 'राजदार' के संवाददाता इकबाल नातिक की १९७७ में खेतवाड़ी में, उसी जगह पर ले जाकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी, जहां कुछ समय पहले वे सब गिरफ्तार हुए थे। उन्हें शक था कि उनकी गिरफ्तारी इकबाल नातिक की मुखबिरी पर हुई थी। इकबाल दाऊद का दोस्त था और अकसर उसकी शह पर करीमलाला के गिरोह के विरुद्ध लिखा करता था। इकबाल की हत्या से

When you are searching your interest areas in an English magazine..

TAKE A

L K

AT

PROBE

INDIA

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe you could look for-sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future for we take a stand on controversial issues.

PROBE

INDIA

Reporting with credibility
that's seeded within.

क्षुब्ध साबिर तथा दाऊद ने समद के साथी सईद बट्टा को पकड़ कर उसी स्थान पर ले जाकर, उसके उस हाथ को बेहरमी से मरोड़ कर तोड़ दिया जिससे उसने इकबाल की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जब नागपाड़ा लाकअप में बंद कर दिया, तो उसके पिता इब्राहीम हक्सर ने जेनाबाई खबरी की सहायता ली। जेनाबाई खबरी ने रज्जी तथा कई नाइट क्लबों के मालिक महेश ढोलकिया की सहायता से साबिर और दाऊद की जमानत करवा दी।

जेल से छूटने के कुछ दिनों बाद ही साबिर व दाऊद ने अमीन जल्लानी नामक एक ट्रैवल एजेंट का अपहरण कर ३ लाख रुपए की फिरौती के रूप में वसूल किये। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। इस रकम से इब्राहीम हक्सर ने अपने दो बेटों साबिर तथा नूरा का विवाह करा दिया। विवाह में 'अंडर वर्ल्ड' के सभी लोग शामिल हुए। उस समय लगा कि उनकी आपस की दुश्मनी खतम हो गयी। लेकिन बाद में घटनेवाली घटनाओं ने दोनों गिरोहों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। उसका परिणाम हुआ भाई साबिर की जघन्य हत्या।

एकाएक भाई साबिर की हत्या से दाऊद बौखला उठा, लेकिन बंबई पुलिस के शिकजे से बचने के लिए वह गुजरात चला गया। वहां से उसने न केवल तस्करी का धंधा शुरू कर दिया, बल्कि सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद में आये दिन वह सांप्रदायिक दंगे करवाने लगा। इस तरह उसने वहां की राजनीति में ऊंची पहुंच बना ली।

एकछत्र साम्राज्य : बंबई में आलमजेब की हत्या के बाद जहां एक तरफ करीमलाला गिरोह कमजोर पड़ गया, वहीं दाऊद बंबई का एकछत्र माफिया डान बन बैठा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एक नये डान की चुनौती का सामना करना पड़ा—महेश ढोलकिया का, जिसका न केवल अपना गिरोह था, बल्कि तस्करी में वह दाऊद का सबल प्रतिद्वंद्वी बन बैठा था। दाऊद अपने धंधे में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बरदाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबल प्रतिद्वंद्वी करीमलाला गिरोह के आदमियों को चुन-चुन कर खतम करवा दिया था।

इस लंबी खूनी जंग ने तीनों गिरोहों को एक बार पुन: सोचने के लिए विवश किया है। वयोवृद्ध माफिया डानों को उनके बीच समझौता कराने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। करीमलाला को सर्वाधिक नुकसान हो चुका था और उनके सारे निजी संबंधी मारे जा चुके थे, ढोलकिया एवं दाऊद के एक-एक भाई की बलि चढ़ गयी थी। उनके कई प्रमुख सरदार भी खेत रहे, इससे उनकी स्थिति काफी कमजोर पड़ गयी थी। जान बचाकर दुबई भाग जाने के कारण दाऊद का भारत में सारा धंधा चौपट हो रहा था, ढोलकिया बंधुओं के व्यवसाय पर भी पुलिस तमाशाई बनकर उनकी जंग को देख रही है, जिसमें वे खुद एक-दूसरे को होम करते जा रहे हैं। इससे सर्वाधिक नुकसान माफिया डानों का ही हो रहा है।

सुलह-सफायी के लिए करीमलाला ने लंदन की यात्रा की, जहां संभवत: उनकी भेंट दाऊद से हुई। अरविंद ढोलकिया भी अब सुलह कर लेना चाहता है और दाऊद भी वापस बंबई लौट आना चाहता है। लेकिन इन सभी माफिया डानों को एक डर सताये हुए है—दाऊद के बंबई वापस लौटने के बाद फिर से माफिया डान के खाली सिंहासन को हथियाने का खूंख्वार दौर शुरू हो जायेगा, जो हाजी मस्तान के सन्यास ले लेने, समद खान, अमीरजादा, आलमजेब की हत्या तथा वरदा भाई की, मौत के कारण खाली पड़ा है। दुबारा खूनी युद्ध न हो, इसकी गारंटी लेने के लिए न तो हाजी मस्तान तैयार हैं, न ही करीमलाला और न ही दूसरे माफिया सरदार। एक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के अनुसार, "जो खूनी खेल उन्होंने खुद शुरू किया है, उसमें उन्हें एक-एक कर अपनी आहुति देनी ही पड़ेगी। रही बात दाऊद के बंबई आकर पुन: सक्रिय होने की, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। या तो उसके दुश्मन उसे मार डालेंगे या हम उसे सींखचों में बंद कर देंगे—वह कितना भी जोर लगाये, लेकिन उसके विरुद्ध इतने मामले दर्ज हैं कि उसे सींखचों के भीतर ही जिंदगी काट देनी पड़ेगी।"

—रवींद्र श्रीवास्तव

LEX ®

★ बनियान
★ जांगिया
★ पेन्टीज़
★ स्पोर्ट-शर्ट

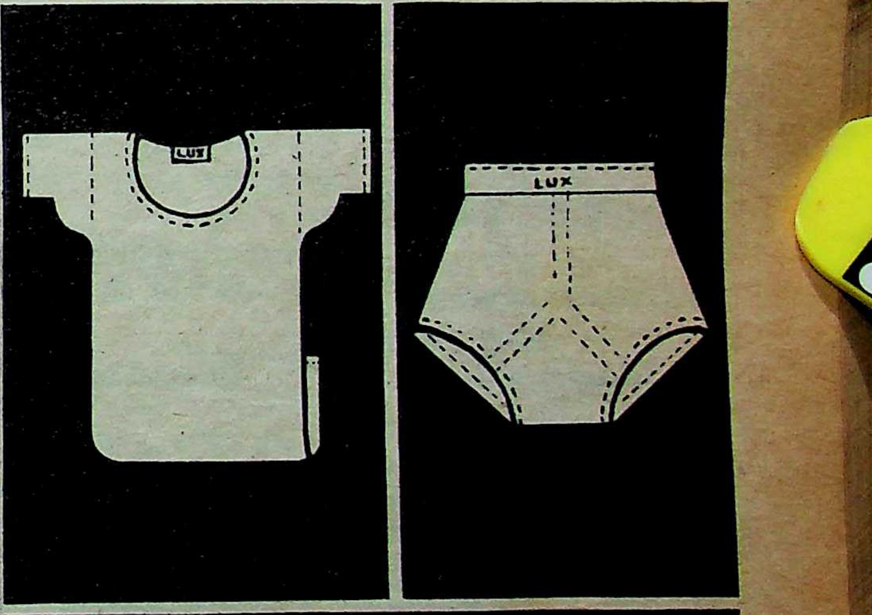

AT
AMRIT TEXTILES

निर्माता :
अमृत
टेक्सटाईल

दूरभाष: ३८-०२५६ कलकत्ता - ७

LOOKAD

शेयर बाजार में नयी जान

सट्टा बाजार लगभग दो साल की गिरावट के बाद सहसा फिर उठ खड़े हुए हैं। अनेक शेयरों ने एक पखवाड़े के दौरान २० से ३० प्रतिशत का लाभांश दिया है। रिलायंस हमेशा की तरह अब भी चोटी पर है। उसके शेयरों में मात्र चार सप्ताहों में लगभग १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक महीने पहले उसकी दर ७० के आसपास थी, जो बढ़कर (१६ मई को) १४३ हो गयी, जबकि कहा जा रहा है कि निजी लोगों में उसका धंधा १६० पर था। बंबई के दो प्रमुख शेयरों, टाटा स्टील और टेल्को ने भी कमाल दिखाया है। इसका रहस्य क्या है?

लागत भत्ता को पुनः शुरू करना भी सट्टा बाजार को मजबूत करने का एक मुद्दा है। उद्योग पिछले दो वर्षों से इसकी मांग करता रहा है। यदि आशानुसार आगामी मानसून बेहतर रहा, तो सट्टा बाजार में और वृद्धि हो सकती है।

वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने लोकसभा में जो घोषणाएं की हैं, उनके ये फौरी नतीजे हैं, किंतु अभी कुछ और होना शेष है। ऐसी खबर है कि लाभांश पर कर पूरी तरह समाप्त कर दिये जा सकते हैं। इसकी जबर्दस्त मांग अनेक हलकों से, खासकर ग्रामीण पूंजीनिवेश की ओर से होती रही है। इनमें से अधिकांश का बैंक एकाउंट नहीं होता। ग्रामीण पूंजी निवेशकों की बाजार में अब अच्छी-खासी गिनती होती है। रिलायंस जैसी कुछ कंपनियों ने उनकी बचत की धारा अपनी ओर मोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये हैं।

लागत भत्ता को पुनः शुरू करना भी सट्टा बाजार को मजबूत करने का एक मुद्दा है। उद्योग पिछले दो वर्षों से इसकी मांग करता रहा है। यदि आशानुसार आगामी मानसून बेहतर रहा, तो सट्टा बाजार में और वृद्धि हो सकती है। इसलिए कुछ विक्रेता अपने शेयरों को अभी बेचने को बहुत उत्सुक नहीं हैं।

विदेशी कर्ज का झूठा सच

भारत का विदेशी कर्ज कितना है? सरकार २४००० करोड़ रुपए से अधिक बताती है और विश्व बैंक ६५००० करोड़ रुपए कहता है। इनमें कौन सही है? सरकार की सही जानकारी के बारे में रवैया बड़ा रहस्यपूर्ण है। वह कहती है कि यह रकम इतनी अधिक नहीं कि इससे पार नहीं पाया जा सकता। विश्व बैंक प्रति वर्ष कर्ज का आंकड़ा प्रकाशित करता है। इसके अनुसार भारत पर हाल की देनदारी लगभग ५००० करोड़ अमरीकी डालर है। रुपए में बदलने पर हाल की विनियम दर से यह ६५००० करोड़ या सरकारी दर से तीन गुनी से अधिक होगी। कौन सच्चा और कौन झूठा है?

विश्व बैंक के अनुसार भारत पर हाल की देनंदारी लगभग ५००० करोड़ असरीकी डालर है। रुपए में बदलने पर हाल की विनियम दर से यह ६५००० करोड़ या सरकारी दर से तीन गुनी से अधिक होगी। कौन सच्चा और कौन झूठा है?

शायद दोनों। सरकार डालर और अन्य मुद्राओं में कर्ज लेती है और उसे उस वर्ष प्रचलित विनिमय दर पर रुपए में बदल लेती है। मसलन, १९७५ में जो १ करोड़ डालर कर्ज लिया गया था, तब उसकी (डालर की) कीमत करीब ८ रुपए से अधिक नहीं थी और यह रकम ८ करोड़ रुपए बैठती थी, किंतु वही रकम अब बहुत अधिक अर्थात लगभग १३ करोड़ होगी। सरकार का कहना है कि वह रकम में इस घटी-बढ़ी का ठीक हिसाब विनिमय दर में परिवर्तन के साथ हर समय तैयार नहीं रख सकती। एक बात और है। सरकार निजी कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों या विदेशों बैंकों से लिये गये कर्जों का लेखा-जोखा नहीं रखती। बहरहाल, इस भारी घपले में एक बात तय है कि भारत के विदेशी कर्ज की रकम का सच सरकार के संकुचित अनुमानों की तुलना में विश्व बैंक के आंकड़े के अधिक निकट है।

अधर में स्कूटर्स इंडिया

ऐसा लगता है कि उ०प्र० सरकार को स्कूटर्स इंडिया लि० से अपना पल्ला झाड़ने में सफलता नहीं मिलेगी। राज्य सरकार अपने इस उद्यम को देश के सबसे बड़े स्कूटर-मोपेड निर्माता संस्थान बजाज आटो के हाथ बेचने का प्रयास पहले कर रही थी। बजाज आटो इस बीमार कपनी को खरीदने को तैयार था जो भारी घाटे का सामना कर रही थी। बजाज का कहना है कि कंपनी को सुचारु रूप से तभी चलाया जा सकता है, जबकि उसे उत्पादक इकाई की जगह एसेंबली (कल-पुर्जे जोड़ने) का कारखाना बना दिया जाये, किंतु शर्त यह है कि इसे पिछड़े क्षेत्र में कायम होने के तमाम लाभ प्राप्त हों तथा कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती कर उसे १००० तक सीमित कर दिया जाये।

इस मुद्दे पर संसद में भी गरमागरम बहस हुई, किंतु केन्द्र ने कहा कि कारखाना भारी घाटे में है, इसलिए उसे अपने पैरों पर खड़ा करने को तैयार किसी इकाई को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

उ०प्र० सरकार चाहती है कि कारखाना स्कूटर बनाना जारी रखे और कल-पुर्जे जोड़ने [illegible] से संबंधित न रहे, क्योंकि ऐसा होने से उसे पिछड़े क्षेत्र में कायम होने के फलस्वरूप मिलनेवाले लाभ— जो सरकार के अनुसार ५ वर्षों में बढ़कर १८० करोड़ रुपए हो जायेगा— से हाथ धोना पड़ेगा। बजाज प्रबंधकों का तर्क है कि कारखाना पुराना पड़ गया है और उसमें परिवर्तन और कर्मचारियों में कमी करना आवश्यक है। दोनों पक्षों के बीच कड़ी सौदेबाजी चल रही है। इस बीच घाटा बढ़ता जा रहा है।

बजाज प्रबंधकों का तर्क है कि कारखाना पुराना पड़ गया है और उसमें परिवर्तन और कर्मचारियों में कमी करना आवश्यक है। दोनों पक्षों के बीच कड़ी सौदेबाजी चल रही है। इस बीच घाटा बढ़ता जा रहा है।

शीतल पेय की गरमी

शीतल पेय ठंडा जरूर है, किंतु इसकी बिक्री गलाकाट प्रतिद्वंद्विता की गरमागरमी से परिपूर्ण है। कारण, तेजी से बढ़ता इसका बाजार इस साल ६०० करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

पार्ले का इस पर वर्चस्व है। आज कुल बाजार का ४४ प्रतिशत भाग पार्ले के पास है, जबकि तीन वर्ष पूर्व यह लगभग ६० प्रतिशत था। यह आश्चर्यजनक नहीं। कारण, उनके तीन ब्रांड (थम्स अप, गोल्ड स्पाट और लिमका) अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों—कोला, आरेंज और लेमन-की बिक्री में अग्रणी हैं। दिल्ली के चरनजीत सिंह के स्वामित्ववाला 'प्योर ड्रिंक्स' नंबर दो पर है, जिसका बाजार पर अधिकार २० प्रतिशत व पार्ले के आधे से कम है। प्योर ड्रिंक्स

का ताजा-तरीन शीतल पेय है, डबल कोला। इसने अपने पहले वर्ष में ही बाजार में अच्छा असर पैदा करके मैकडावल्स को पछाड़ दिया है और अन्य नामी-गिरामी कंपनियों, मसलन पार्ले और प्योर डिंक्स की नींद हराम कर दी है। डबल कोला ने बाजार के १० प्रतिशत पर अधिकार जमा लिया है। इसमें से इसने आधा बाजार प्योर डिंक्स से हथियाया है जो ३० वर्ष से इस व्यवसाय में है।

पार्ले के देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोतलबंदी के ५६ और विदेशों में १२ कारखाने हैं। पश्चिम क्षेत्र—बंबई व अहमदाबाद—में इसकी सर्वाधिक खपत है जो कुल बिक्री का लगभग ४० प्रतिशत होती है। प्योर ड्रिंक्स जब कोका कोला की बिक्री करता था, तब चोटी पर हुआ करता था। उसके पार्ले से आधे-३२ बिक्री-क्षेत्र हैं। डबल कोला गत वर्ष ही भारत में आया है, किंतु यह १७ क्षेत्रों को हथियाने में सफल रहा है, यद्यपि इसकी बिक्री कमोबेश बंबई और दक्षिण तक ही सीमित है। इसने पार्ले के बंबई के बाजार पर गहरी चोट की है और अब वह उत्तर को फतह करने में लगा है।

> डबल कोला गत वर्ष ही भारत में आया है, किंतु यह १७ क्षेत्रों को हथियाने में सफल रहा है, यद्यपि इसकी बिक्री कमोबेश बंबई और दक्षिण तक ही सीमित है। इसने पार्ले के बंबई के बाजार पर गहरी चोट की है और अब वह उत्तर को फतह करने में लगा है।

एसीसी का अधिग्रहण ?

यदि आपको यह पता लगे कि कुछ निजी पूंजी निवेशकों ने 'टाटा स्टील' के काफी तादाद में शेयर खरीद लिये हैं और अब वे टाटाओं से यह कंपनी हथियाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी (एसीसी) के साथ हुआ है जो देश में सीमेंट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। कलकत्ता के महेंद्र स्वरूप नामक एक व्यक्ति ने (जिसने प्रोसेसिंग उद्योग को कूलिंग टावर्स की आपूर्ति के धंधे से मोटी कमाई की है), हाल में एसीसी के ५ करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे हैं। यह कंपनी टाटा के नियंत्रण में है और ननी पालकीवाला इसके चेयरमैन हैं। इस प्रकार महेंद्र स्वरूप कंपनी की ७ प्रतिशत संपत्ति पर अधिकार जमा कर सबसे बड़े शेयरधारी बन गये हैं। खटाऊ, मिस्त्री, हीराचंद और नस्ली वाडिया जैसे औद्योगिक समूहों की मिलीजुली शक्ति भी एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

> स्वरूप
>
> एसीसी कंपनी का प्रबंध हाथ में लेने में सफल हो सकते हैं, जिसकी परिसंपत्तियां ४०० करोड़ रुपए की हैं और जिसकी प्रतिवर्ष बिक्री ८०० करोड़ रुपए से अधिक है; गोकि स्वरूप ने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है।

इस प्रकार स्वरूप एसीसी कंपनी का प्रबंध हाथ में लेने में सफल हो सकते हैं, जिसकी परिसंपत्तियां ४०० करोड़ रुपए की हैं और जिसकी प्रतिवर्ष बिक्री ८०० करोड़ रुपए से अधिक है; गोकि स्वरूप ने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है। स्वरूप ने जिन चार लाख डिबेंचरों के लिए आवेदन किया था, वह उन्हें प्राप्त हो गये थे। नस्ली वाडिया और मिस्त्री ने भी आवेदन किया था। किंतु इन लोगों ने 'बेनामी' नामों पर आवेदन किया था, इसलिए वह नामंजूर कर दिया गया था।

स्वरूप ने स्वदेशी पालिटेक्स के अधिग्रहण का प्रयास भी गत वर्ष किया था, किंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली।

जय दुबाशी

नये आसान और असरकारक तरीके से

अपना पेट सपाट बनाइए !

सिर्फ ५ मिनट की कसरत हैरतअंगेज असर दिखाए, जिसे आप देख, महसूस और नाप सकते हैं.

आपका पेट सपाट बनाए.
जांघे सुडौल बनाए... कूल्हे मजबूत बनाए
पूरे शरीर को सशक्त और फुर्तीला बनाए.
सही नतीजों की गारंटी वर्ना पैसे वापस !

बुलवर्कर का टमी ट्रिमर

इस्तेमाल में आसान है, शरीर को तेज़ी से छरहरा बनाने की ख्वाहिश रखनेवाले लोगों के लिए वरदान है. आइसोटोनिक के सिद्धान्तों पर आधारित है यह, जो आपको देता है रोइंग के तेज़ और असरकारक फायदे बुलवर्कर का **टमी ट्रिमर** आपकी मांसपेशियों को सशक्त और फुर्तीला बनाता है, चर्बी घटाता है, साथ ही आपको सुडौल, आकर्षक और ताकतवर शरीर देता है— वो भी बड़ी आसानी से.

आराम से इंच-इंच बदन को तराशिए, चुस्त रखिये— वो भी बिना जोखिम. अपने घर में ही वर्जिश के इस क्रमवार कार्यक्रम को पूरे इत्मीनान के साथ कीजिए और फर्क खुद देखिए. यदि घर में ही की जानेवाली १४ दिन की इस मुफ्त आजमाइश से आप पूरी तरह संतुष्ट न हों तो इसे लौटा दीजिए और अपना पैसा वापस ले लीजिए— कोई सवाल-जवाब नहीं होगा.

१४ दिनों तक बिना— जोखिम मुफ्त आजमाइश !

अभी फैसला कीजिए ! **टमी ट्रिमर** के साथ मुफ्त मिलेगा एक चर्बी-मापक— परिणामों को रोज-दर-रोज नापने के लिए !

बुलवर्कर का टमी ट्रिमर दो मॉडेलों में उपलब्ध :

रेग्युलर मॉडल	एक स्प्रिंग के साथ रु. 195 में
सुपर मॉडल	दो स्प्रिंगों के साथ रु. 240/-में

बुलवर्कर प्रा. लि.
१५ मैथ्यू रोड, बंबई-४०० ००४.

ABHA

यह कूपन आज ही भेजिए !

बुलवर्कर प्रा. लि. १५, मैथ्यू रोड, बम्बई-४०० ००४. TT-607-H

कृपया मुझे १४ दिनों की मुफ्त आजमाइश के लिए नीचे बताये गये नये टमी ट्रिमर का मॉडल फौरन भेज दीजिए. अगर मैं इसके नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट न हुआ/हुई, तो पैसे (डाक व प्रेषण खर्च घटा कर) वापस पाने के लिए आजमाइशी अवधि के भीतर सारी सामग्री लौट दूंगा/दूंगी. बिना किसी सवाल जवाब के !

MY-59

अपनी पसंद का मॉडल चुनिए/आजमाइए

☐ रेग्युलर मॉडल— एक स्प्रिंग के साथ, कीमत रु 195/- ☐ सुपर मॉडल— दो स्प्रिंग के साथ, कीमत रु 240/-

कृपया उचित खाने में ☑ निशान लगायें.

☐ रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से भेजें. मैं रु .... ड्राफ्ट/आइ पी.ओ./मनी ऑर्डर न........ दिनाक.......... भेज रहा हूं/रही हूं. (बुलवर्कर प्रा. लि. को देय)

☐ वी.पी.पी. से भेजें. मैं डाकिए को डिलीवरी मिलने पर रु............अदा करने का वचन देता हूं/देती हूं.

नाम..

पता..

....

पिन .... हस्ताक्षर ....

मेरी दुनिया ही पलट जाती...

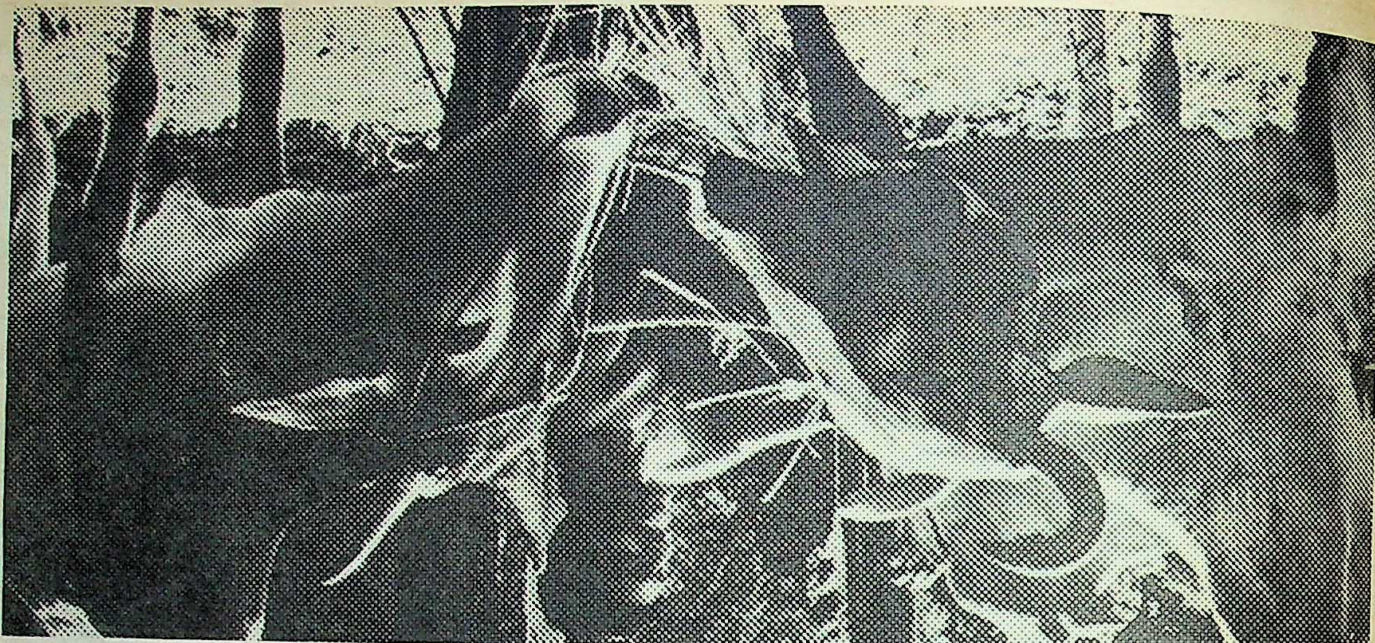

अगर मैं न्यू इन्डिया से पशुधन बीमा न करवाता.

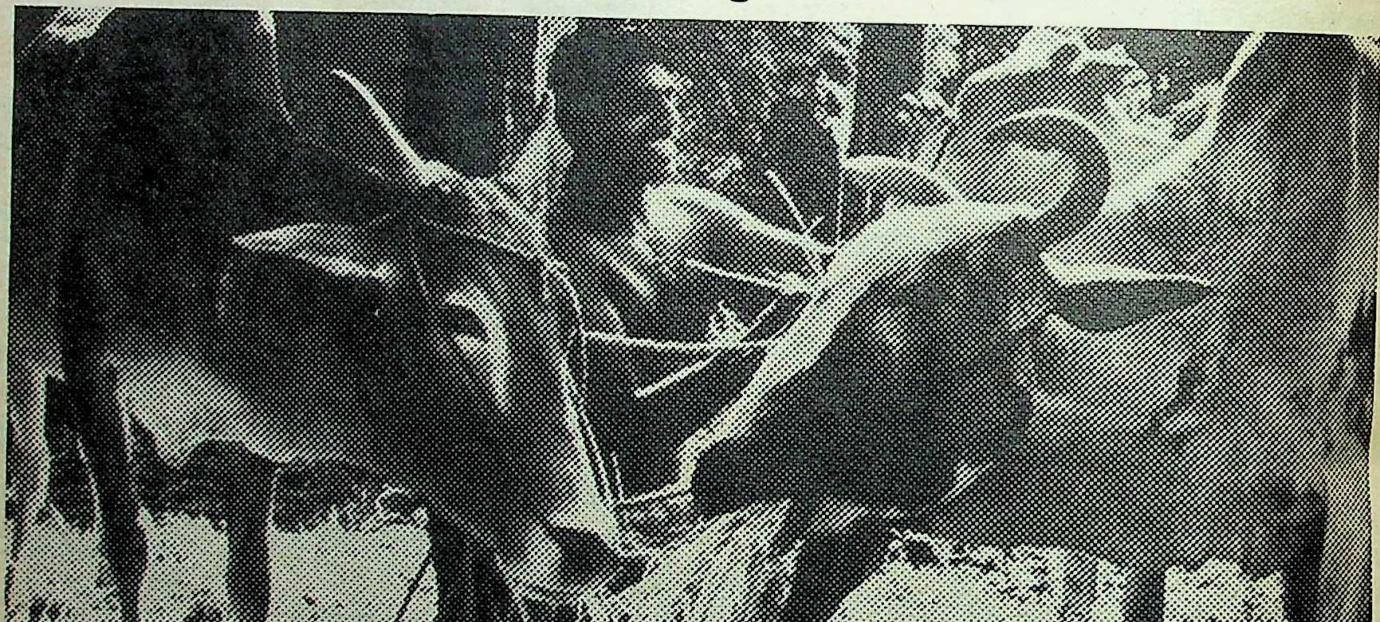

मेरे बैल मर गए लेकिन काम नहीं रुका.
क्योंकि न्यू इन्डिया की बदौलत मैं नए बैल ख़रीद सका.

एक किसान के लिए उसके बैल कितने मूल्यवान होते हैं, यह बात वह और उसके परिवारवाले अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन वे ही बैल अगर बीमार पड़ जाएं, दुर्घटना में बेकार हो जाएं ... या मर जाएं तो? ऐसे में, न्यू इन्डिया एश्योरन्स एक सच्चे मित्र की तरह उसका सहारा बनता है.

पशुधन बीमा – न्यू इन्डिया एश्योरन्स का
सालभर में, जानवर की कीमत के हर 100 रुपए पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपए देने पड़ते हैं ... बस! देशभर में न्यू इन्डिया एश्योरन्स के लगभग 1000 कार्यालय हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही एजेंट से मिलें या अपने नज़दीकी कार्यालय में पधारें.

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक सहायक कंपनी

पशुधन बिमा – नुकसान में आपका सहारा!

R.K.SWAMY/NIA/3574B/HIN

स्टीलेज

अग्निरोधक आलमारियां

आग और पानी मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं। इनके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आग और पानी का प्रकोप उसके बने बनाये संसार को मटियामेट भी कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य आग और पानी से बचाव के साधनों को भी सतत विकसित करता रहा है। आग, पानी से कहीं अधिक घातक साबित होती है। उसकी चपेट में आनेवाली हर वस्तु पल भर में खाक हो जाती है। लेकिन हाल ही एक भारतीय कंपनी 'स्टीलेज' ने 'न्यू एज' नामक एक ऐसी अग्निरोधक आलमारी बनाने में सफलता पा ली है जो कंपनी के दावे के अनुसार १००० डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापवाली भट्टी में झोंक दिये जाने पर भी अपने अंदर रखे दस्तावेजों, फाइलों और नगदी रोकड़ पर आंच नहीं आने देती, जबकि आमतौर पर १७७ डिग्री सेंटीग्रेड पर कागज जलने लगता है। कंपनी के दावे के अनुसार रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इन अग्निरोधक आलमारियों का सख्ती और सावधानी से परीक्षण कर इसकी अग्निरोधक क्षमता की तांकीद कर दी है। परीक्षण के तौर पर ऐसी अग्निरोधक आलमारी में कागजात और फाइलें भर दी गयीं। इस आलमारी को एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापवाली भट्ठी में रखा गया। एक घंटे बाद आलमारी भट्ठी से बाहर निकाली गयी और ४ मीटर की ऊंचाई से ईंट के रोड़ों की ३० सेमी मोटी एक परत पर गिरायी गयी। इसके बाद उसे फिर एक घंटे तक भट्ठी में पहले की तरह ही रखा गया। दुबारा गरम हो जाने पर इस आलमारी को भट्ठी से निकाल लिया गया और इतना ठंडा किया गया, ताकि उसे खोला जा सके। परीक्षण के दौरान पेटी के अंदर खाली जगह का तापमान उसके हर दराज में लगे दो उष्म-युग्मों (थर्मोकपुल्स) से मापा गया। भट्ठी का तापमान जब १०२६डिग्री सेंटीग्रेड था, तो भी पेटी के अंदर का तापमान १७० डिग्री सेंटीग्रेड से कम था और दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दस्तावेजों में सिर्फ हलका-सा भूरापन आ गया था।

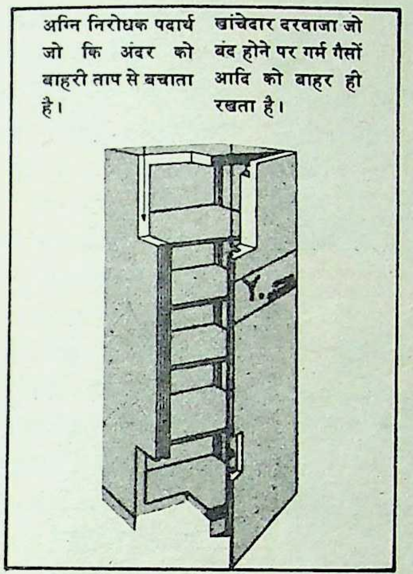
अग्नि निरोधक पदार्थ जो कि अंदर को बाहरी ताप से बचाता है।
खांचेदार दरवाजा जो बंद होने पर गर्म गैसों आदि को बाहर ही रखता है।

डाटा गार्ड आलमारी

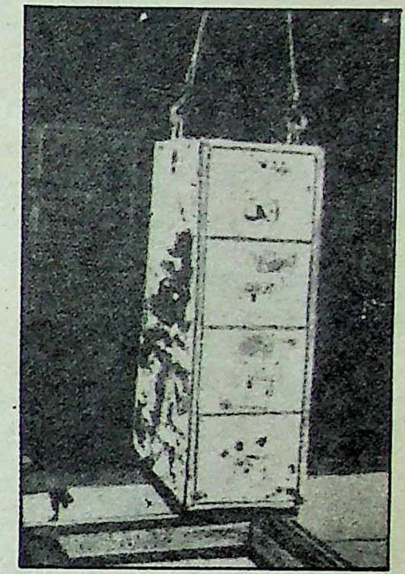

दो घंटे के आग सहनशक्ति परीक्षण के बाद बाहर निकलता कैबिनेट

डाटा गार्ड: आग से इतना ही बड़ा खतरा कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को भी है। कंप्यूटरों के मामले में तो गरम काफी के प्याले का ताप भी तबाही मचा सकता है। कागज जहां १७७ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर झुलसता है, वहां कंप्यूटर से तैयार डाटा संग्रहीत करने वाली नाजुक 'फ्लापी डिस्क' ६६ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान या ८५ प्रतिशत से अधिक नमी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती हैं। उन पर रिकार्ड किये गये संकेत मिट जाते हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव तक का उन पर बुरा असर पड़ता है। यह डिस्क सिर्फ गरमी के दिन की धूप में छोड़ दिये जाने से ही नष्ट हो सकता है। साधारण फाइल की दराज में रखे डिस्क या टेप बगल की रद्दी कागजोंवाली टोकरी में जरा-सी आग लग जाने से भी किसी काम के नहीं रहते। ऐसी नाजुक चीजों को आग से बचाने के लिए इस कंपनी ने 'डाटा गार्ड' नामक आलमारी का निर्माण किया है। स्टीलेज के अनुसार उसकी 'डाटा गार्ड' आलमारी सब तरह के कंप्यूटर-रिकार्डों को आग व विस्फोट से उत्पन्न भीषण ताप से भी बचा लेने में सक्षम है। कहा जाता है कि नमी न आने देने के लिए यह आलमारी अंदर से वायु शून्य कर बंद कर दी जाती है, क्योंकि आलमारी के अंदर ६६ डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी नमी आ जाने पर 'डाटा रिकार्ड' बरबाद हो सकते हैं।

इस 'डाटा गार्ड' में दो खाने होते हैं। एक के भीतर दूसरा खाना बना होता है। दोनों के बीच १२ मिमी की दूरी होती है। इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे उसमें भाप, नमी, उच्च ताप को घुसने से रोका जा सके और भीषण आग की चपेट में आने पर भी आलमारी के भीतर का तापमान चुंबकीय टेपों को क्षतिग्रस्त करने की हद तक न बढ़ने पाये।

कंपनी का दावा है कि 'डाटा गार्ड' का भीतरी भाग खासकर कंप्यूटर-रिकार्ड और चुंबकीय टेप रखने के लिए ही बनाया गया है। इस भाग में ३० करोड़ों-करोड़ सूचना-संकेतों से युक्त ०.३ मी लंबा चुंबकीय 'टेप रिकार्ड' रखा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस १.७८ मी० लंबी 'डाटा गार्ड' पेटी में पांच-पांच सौ पृष्टों की ३ लाख अरब पुस्तकों में आनेवाली जानकारियों से भी अधिक जानकारियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं।

माइक्रो फायर आलमारी: स्टीलेज ने 'डाटा गार्ड' का एक लघु रूप भी विकसित किया है। 'माइक्रो फायर कैबिनेट' नामक यह आलमारी भी आग, धूल, आर्द्रता व चुंबकीय दुष्प्रभावों और दुर्घटनाओं से नाजुक रिकार्डों को बचाने के लिए बनायी गयी है।

मशीनों, उपकरणों, भवनों एवं अन्य वस्तुओं का बीमा हो सकता है। इनके नष्ट होने पर इन्हें बदला जा सकता है, लेकिन आंकड़ों को न तो बदला जा सकता है और न ही इनका बीमा हो सकता है, जबकि कंप्यूटर व्यवसाय में आंकड़ें ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में स्टीलेज कंपनी की अग्निरोधक आलमारियां हर व्यवसाय के लिए अपरिहार्य बन गयी हैं।

—अभय अग्रवाल

'जेड-७५' : सफायी करनेवाली मशीन

यूरेका फोरबेस कंपनी ने होटलों, दुकानों, उद्योगों और घरों आदि की झाड़-पोंछ और सफायी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 'जेड-७५ कम्पेक्ट हैवी ड्यूटी वेक्यूम क्लीनर' नाम से एक मशीन का निर्माण किया है। यह मशीन फर्श, छत, कालीनों, दीवारों और खिड़कियों में जमा गर्द और पानी को चूस लेती है। इतना ही नहीं, कंप्यूटरों और उन्नत किस्म के विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सफायी भी यह बखूबी करती है।

जेड-७५ नामक इस सफायी मशीन में दो शक्तिशाली मोटरें लगी हैं जिनसे यह १६०० मिमी पानी सोख सकती है और ३.५ घन मीटर प्रति मिनट की गति से हवा छोड़ सकती है। इस मशीन में दस लीटर गर्द रखने की क्षमतावाला एक थैला भी रहता है और पूरी मशीन का वजन सिर्फ १८ किलोग्राम है। इसका डिजायन इस प्रकार तैयार किया गया है, जिससे इसे चलाने में आसानी हो और लंबे समय तक इससे काम लिया जा सके। यूरेका फोरबेस कंपनी ने इस मशीन को जून, १६८६ में बाजार में पेश किया था और आज अनेक औद्यौगिक प्रतिष्ठान व होटल इस मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। देश भर में इस कंपनी ने ४० सेवा केंद्र स्थापित किये हैं, जो इन मशीनों के रखरखाव का मार्गदर्शन देने व खराब हो गयी मशीनों की मरम्मत करने के लिए सदैव तत्पर हैं।

देश

१६ मई: पंजाब में अलग-अलग घटनाओं में आतंकवादियों द्वारा १३ व्यक्तियों की हत्या। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संयुक्त गश्त पर सहमति।

१७ मई: आतंकवादियों द्वारा पंजाब में १७ लोगों की हत्या। औरंगाबाद में एक सांप्रदायिक दंगे में ५ मरे, शहर में कर्फ्यू।

१८ मई: स्वर्ण मंदिर परिसर आतंकवादियों से पूर्णतया मुक्त। औरंगाबाद में २ मरे, १० घायल, कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने का आदेश। इफ्को के आंवला (मुरादाबाद) उर्वरक कारखाने में उत्पादन शुरू।

१९ मई: राष्ट्रपति वेंकटरमण द्वारा बेनामी हस्तांतरण (प्रतिबंध) अध्यादेश की घोषणा। देश के प्रथम राष्ट्रीय चैनल (आकाशवाणी) से प्रसारण शुरू। राष्ट्रपति द्वारा बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण हेतु अध्यादेश जारी।

२० मई: आतंकवादियों द्वारा पंजाब और हरियाणा में ४५ लोगों की हत्या। स्वर्ण मंदिर में आपरेशन 'ब्लैक थंडर' के बाद कर सेवा शुरू।

२१ मई: अजीत सिंह जनता पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बने। गोरखालैंड उग्रवादियों द्वारा प० बंगाल के पहाड़ी मामलों के मंत्री तमांग दवाल लामा की हत्या का प्रयास।

२२ मई: स्वर्ण मंदिर जनता के दर्शनों के लिए खुला, मर्यादा को पुनः बहाल किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रामाराव द्वारा कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान।

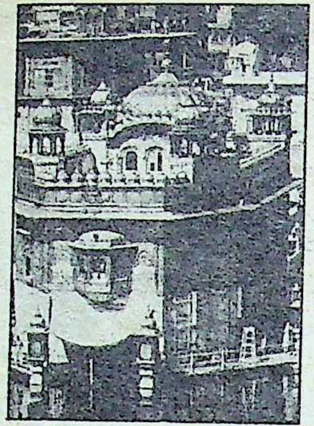

स्वर्ण मंदिर

द्वारिका प्रसाद मिश्र

२३ मई: इलाहाबाद (संसदीय) उपचुनाव के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुनील शास्त्री और कांशीराम द्वारा नामांकन। जी पार्थसारथी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त।

२४ मई: पंजाब में १७ की हत्या और ९ को जिंदा जलाने की कोशिश। इनसैट-१ सी के प्रक्षेपण का कार्यक्रम शुरू।

२५ मई: सरकार द्वारा दूरदर्शन का दूसरा चैनल राज्यों को देने से इनकार। पंजाब में ३ आतंकवादियों सहित १५ मरे। असम के बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री उत्पल दत्त बरखास्त।

२६ मई: धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग रोकने के लिए अध्यादेश जारी। किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई स्थगित। उपराष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा का द० अफ्रीका के खिलाफ व्यापक पाबंदी का आह्वान। पंजाब में रासुका की अवधि एक साल के लिए बढ़ी। स्वर्ण मंदिर के आसपास गलियारा बनाने का निर्णय।

२७ मई: शस्त्र कानून को और सख्त बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। पंजाब में कुख्यात आतंकवादी अवतार सिंह सहित ९ मारे गये। चुनाव आयोग द्वारा ३ जुलाई को कर्नाटक विधान परिषद का चुनाव कराने की घोषणा।

२८ मई: विजयवाड़ा में दस विपक्षी दलों द्वारा अगला चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति।

२९ मई: प्रकाश सिंह बादल सहित छह अन्य एकीकृत अकाली दल के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार। पंजाब में कांग्रेस के नेता सहित १० की हत्या।

३० मई: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा सभी पांच मुख्यग्रंथी बरखास्त। किरण बेदी की जमानत मंजूर।

३१ मई: मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का निधन। भारत-पाक विदेश सचिवों की बैठक शुरू।

■

विदेश

१६ मई: अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डा० नजीबुल्लाह द्वारा अफगान विद्रोहियों को सरकार में शामिल होने का निमत्रण।

१७ मई: सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान को विभाजित करने के आरोप का खंडन।

१८ मई: श्रीलंका के राष्ट्रपति पहली बार वरिष्ठ लिट्टे नेता से मिले।

१९ मई: अमरीका द्वारा पाकिस्तान को १४.३ बिलियन डालर की सहायता। रूस और पाकिस्तान विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए मंत्रिस्तर के एक संयुक्त आयोग के गठन पर राजी।

२० मई: सियाचिन मुद्दे पर भारत-पाक वार्ता इस्लामाबाद में खतम। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सचिव नंदलाल फर्नेंडों की हत्या। नेपाल के शिक्षामंत्री केबी विष्ट का इस्तीफा मंजूर।

२१ मई: संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव दियोगो कारदोवेज इक्वेडोर के राष्ट्रपति द्वारा अगले विदेश मंत्री नामांकित।

२२ मई: चीन ने ९वीं एशियाई टेबिल टेनिस एकल प्रतियोगिता जीती। श्रीलंका में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी डीए शेखर समेत ८ की हत्या।

२३ मई: २३ लिट्टे उग्रवादी शांति सेना द्वारा मारे गये।

२४ मई: न्यूयार्क टाइम्स में पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण की रपट। वाशिंगटन में गांधी स्मारक बनाने के प्रस्ताव का अमरीकी कांग्रेस उपसमिति का सर्वसम्मति से समर्थन।

जयवर्धने

जियाउलहक

२५ मई: थामस कप में चीन से हारकर भारत प्रतियोगिता से बाहर। अमरीकी रक्षा विभाग द्वारा पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र परीक्षण का खंडन। लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी द्वारा चाड युद्ध समाप्ति की घोषणा।

२६ मई: मुहम्मद हसन शर्क नये अफगान प्रधानमंत्री। अफ्रीका एकता संगठन द्वारा अफ्रीकी मानवाधिकार आयोग को जांबिया में स्थापित करने का फैसला।

२७ मई: भारत मानवाधिकार आयोग का पुनः सदस्य निर्वाचित। अमरीकी सीनेट द्वारा मध्यम दूरी परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि की पुष्टि।

२८ मई: भारत और चीन के बीच पहला सांस्कृतिक समझौता।

२९ मई: पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया द्वारा जुनेजो सरकार बरखास्त। राष्ट्रपति रीगन मास्को पहुंचे, शिखर वार्ता शुरू। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा मास्को शिखर वार्ता में भाग ले रहे राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गोर्बाचोव से इस साल के अंत तक हथियारों के खर्चे पर पचास प्रतिशत कटौती करने की अपील।

३० मई: पाकिस्तान के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर पहुंचे। चीन थामस और उबेर कप प्रतियोगिता के फाइनल में। फ्रेंच ओपेन में विंबलडन चैंपियन बोरिस वेकर पराजित। भारत-श्रीलंका समझौते पर विचार-विमर्श के लिए रक्षामंत्री केसी पंत लंका पहुंचे।

३१ मई: प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण की अग्रिम सूचना एक दूसरे को देने पर महाशक्तियां राजी। ■

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब ...

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद, वाह! क्या लाजबाब.......

रश्मि ज़र्दा

Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
FLAVOURED CHEWING TOBACCO
SATYAPAL SHIVKUMAR
355, NAYA BANS DELHI-110006

सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006

(वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

BLISS/DEL

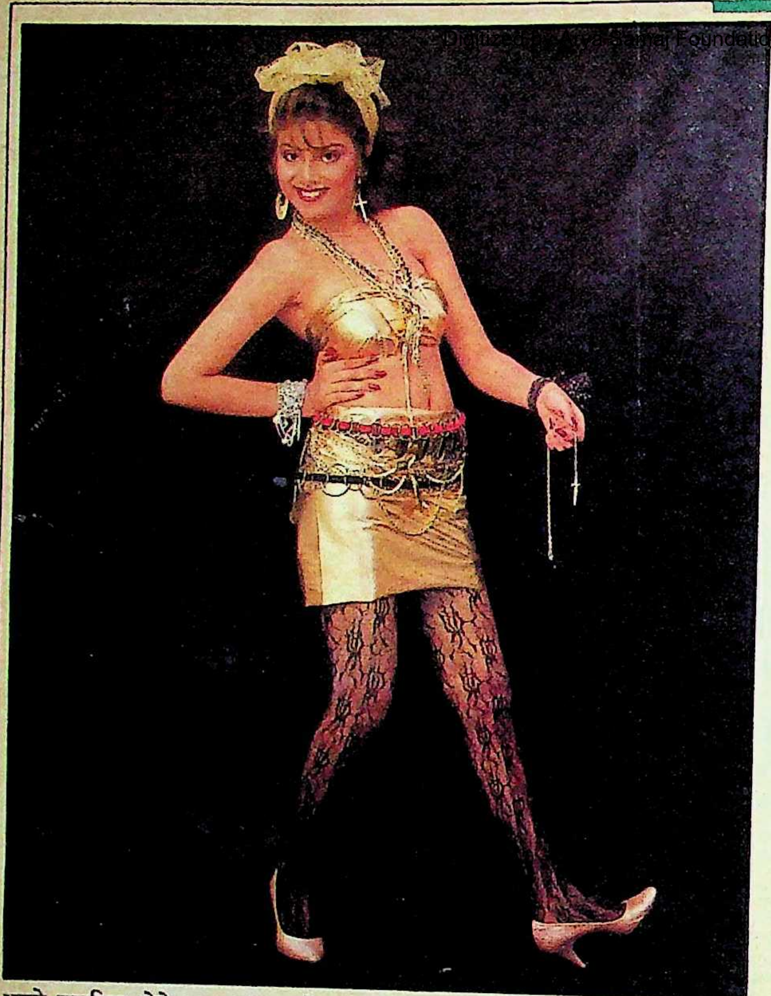

अपने कमसिन होने का बखान : सोनम

छाया : तैयब बादशाह

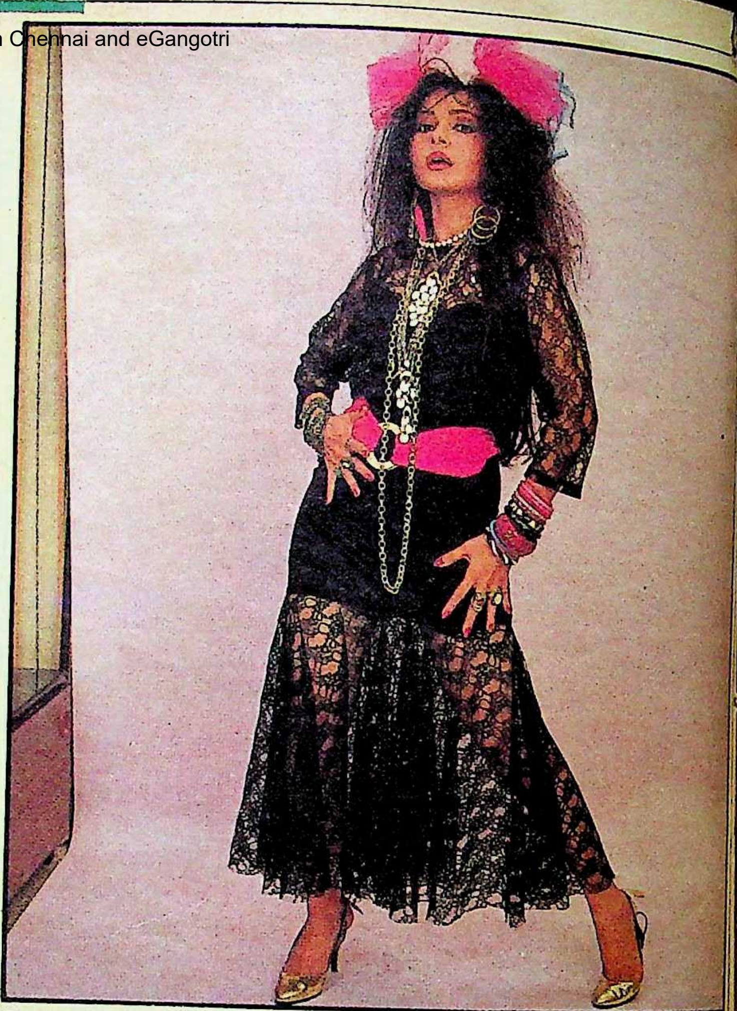

स्मिता-शबाना की परंपरा की अभिनेत्री : सुजाता मेहता

छाया : तैयब बादशाह

सोनम और सुजाता मेहता

जरूरत प्रतिभा की या ग्लैमर की ?

व्यावसायिक फिल्मों की भेड़चाल में भी स्मिता पाटील और शबाना आजमी ने कला फिल्मों के जरिये अपनी एक अलग इमेज खड़ी करके स्टार होने तक का खिताब हासिल किया, पर इधर व्यावसायिकता ने इतना पांव पसार लिया है कि स्मिता-शबाना की परंपरा की एक अभिनेत्री सुजाता मेहता प्रतिभा के होते हुए भी फिल्में नहीं हथिया पा रही है, जबकि पंद्रह वर्षीया सोनम बिना किसी फिल्म के प्रदर्शित हुए—एक वर्ष में ही न केवल सुपर स्टार बन गयी, बल्कि वह लगभग ७५ फिल्मों में काम कर रही है और उस पर फिल्म इंडस्ट्री का ५० करोड़ रुपये लगा हुआ है। क्या ग्लैमर के आगे अब प्रतिभा की कद्र नहीं है फिल्मी दुनिया में—या सुजाता मेहता के मुकाबले सोनम में कुछ और खास बात है ? ग्लैमर की चकाचौंध यदि इसी तरह जगमगाती रही, तो प्रतिभा संपन्न अभिनेत्रियों का क्या होगा ?

१९८७ में फिल्म उद्योग में देखने में मामूली, लेकिन परिणाम से महत्वपूर्ण दो घटनाए हुई थीं। निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी नयी फिल्म 'विजय' के लिए १५ वर्ष की एक खूबसूरत लड़की को ऋषि कपूर की नायिका [illegible] में अनुबंधित किया और एक वर्ष के भीतर ही वह लड़की, बिना एक भी फिल्म प्रदर्शित हुए, सबसे अधिक फिल्मोंवाली सुपर स्टार बन बैठी। २५ हजार रुपए के मामूली पारिश्रमिक से शुरू होने वाला उसका कैरियर एक वर्ष के ही भीतर छह लाख रुपए की मार्केट वैल्यू तक पहुंच गया, जिसमें हर महीने नये शून्यों, नये अंकों का इजाफा अपने आप होने लगा है। फिल्म इंडस्ट्री के स्टारडम में ऐसा हादसा अभी तक, इस रूप में, पहले कभी नहीं हुआ था। और यह लड़की है सोनम, जो चंकी पांडे से लेकर देवआनंद तक के साथ काम कर रही है और जिसने ७५ से भी अधिक फिल्में साइन कर रखी हैं, यानी जिस पर फिल्म इंडस्ट्री का ५० करोड़ से अधिक रुपया लगा हुआ है।

दूसरी घटना थी एक ऐसी अभिनेत्री की, जिसे फिल्मों में काम करने से कभी गुरेज था और कई आफर लौटा चुकी थी, जबकि मराठी रंगमंच की न केवल वह जानी-मानी अभिनेत्री थी, बल्कि 'खानदान' तथा 'श्रीकांत' टीवी सीरियलों से अपने अभिनय की पहचान कायम कर चुकी थी। कम बजट वाली उसकी फिल्म १९८७ की सर्वाधिक

लाभ देनेवाली फिल्म थी। वह अभिनेत्री है—सुजाता मेहता तथा फिल्म थी 'प्रतिघात'।

यह दुर्भाग्य ही था कि सबसे ज्यादा लाभ देनेवाली सुपरहिट 'प्रतिघात' की नायिका सुजाता मेहता के घर दस्तक देने के बजाय निर्माता सोनम के पीछे चक्कर लगाते रहे, जबकि 'मि० इंडिया' तथा 'नगीना' की नायिका श्रीदेवी ने इन दोनों फिल्मों की बाक्स आफिस सफलता के बाद अपनी प्राइस में पांच लाख तथा कुछ नयी शर्तें और जोड़ दीं। 'खानदान', 'श्रीकांत' तथा 'प्रतिघात' से बनी भारतीय नारी की इमेज को तोड़ने के लिए उसने ग्लैमरस तथा माड लड़की के चित्र खिचवाकर फिल्म पत्रिकाओं में छपवाने शुरू किये, लेकिन ग्लैमर, अंग-प्रदर्शन तथा सेक्स को 'दर्शकों को लुभानेवाला रामबाण नुस्खा' माननेवाले फिल्म निर्माता यह विश्वास ही नहीं कर पाये कि ये विशेषताएं सुजाता मेहता में भी हैं, न तो उन्हें भारतीय नारी की इमेजवाली सुजाता मेहता में दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने का माद्दा नजर आया और न ही सुपर हिट हो जाने के बावजूद 'प्रतिघात' जैसी फिल्में दुबारा बनाने की उन्हें प्रेरणा ही मिली। इसका फल यह हुआ कि अपनी सारी अभिनय-प्रतिभाओं के बावजूद सुजाता को सिर्फ इमेज के कारण उस सोनम से हार मान लेनी पड़ी, जिसके पास फिल्मों के अनुबंध के जखीरे तो थे, लेकिन अपनी अभिनय-प्रतिभा से वह किसी को भी चमत्कृत नहीं कर पायी है। कितना चमत्कृत कर पायेगी, यह तो यश चोपड़ा की फिल्म 'विजय' से ही पता चलेगा, जो शीघ्र ही प्रदर्शित होनेवाली है,

मराठी नाटक 'चीत्कार' से रंगमंच की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच जानेवाली सुजाता मेहता इस समय विक्रम सिंह देवल, रमेश सिप्पी, बीआर चोपड़ा, सोहनलाल कंवर की फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं (नायिका की नहीं) निभा रही है। सुजाता का टीवी सीरियल 'श्रीकांत' बीबीसी पर दिखलाये जाने के साथ-साथ इसे १६ एमएम से ३५ एमएम में ब्लो अप करके सिनेमाघरों में भी प्रदर्शित करने की तैयारी चल रही है।

पढ़ाई से मुंह चुरानेवाली सोनम की हर सप्ताह कम-से-कम दो फिल्मों का मुहूरत होता है। वह रिश्ते में चरित्र अभिनेता रजा मुराद तथा जानी-मानी ड्रेस डिजाइनर साबिया की भांजी है। खुले अंग-प्रदर्शन के सवाल पर तुर्की-ब-तुर्की जवाब देती है, "मेरे पास अगर फिगर है, तो उसे प्रदर्शित करने में बुराई क्या है?" 'मेकअप' तथा 'फिगर मेनटेन' रखने की बात का भी जवाब उसके पास है, "यह सब तो उन्हें जरूरत पड़ती है, जिनकी उम्र ढलने लगती है, मुझे क्या जरूरत? अभी तो मैं खुद ही कमसिन हूं।"

लेकिन सुजाता और सोनम में एक समानता है कि दोनों के नखरे सुर्खियों का तथा फिल्म निर्माताओं की शिकायतों का विषय बने रहते हैं। एक भुक्तभोगी फिल्म निर्माता के अनुसार, "इन अभिनेत्रियों में तो यही बुराई है। कोई फिल्म हिट हो गयी या ज्यादा फिल्में मिल गयीं, तो उनके दिमाग इस तरह सातवें आसमान पर जा पहुंचते हैं कि वे भूल जाती हैं कि उनको बनानेवाले और बिगाड़नेवाले फिल्म निर्माता ही हैं। उन्हें परेशान कर आप कितने दिन टिक सकेंगी इस इंडस्ट्री में।" एक निर्देशक का कहना था, "ये सभी लोग नर्गिस, मीना कुमारी और वहीदा रहमान बनना तो चाहती हैं, लेकिन इनके बीहैवियर? मत पूछिए। बादशाहत के दिनों में सिरफिरी राजकुमारियां-नवाबजादियां भी ऐसा नहीं करती होंगी।"

सोनम दो-दो शिफ्टों में (१५ घंटे) शूटिंग करती है। सुजाता मेहता सप्ताह में तीन-चार दिन एवरेज से शूटिंग करती है, कभी नाटकों की मंच-प्रस्तुति होती है, तो उसमें भी भाग लेती है। वह शबाना आजमी और स्मिता पाटील की परंपरा की अभिनेत्री है और कुछ लोगों ने उसे स्व० स्मिता पाटील का विकल्प भी मान लिया है। फिल्म निर्माताओं के अनुसार वह निस्संदेह बेहतरीन फिल्म अभिनेत्री है, बहन-भाभी की भूमिका में खूब जंचेगी, लेकिन नायक के साथ नाचती-गाती या डिस्को करती सुजाता को दर्शक बरदाश्त नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए वह बिकनी पहनने के लिए ही क्यों न तैयार हो जाये। इसमें तो सोनम जैसी अभिनेत्रिया ही जंचेंगी। इसलिए सुजाता को साइड रोल ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी अभिनेत्रियों की फिल्म इंडस्ट्री में काफी कमी है, लेकिन सुजाता इस बात को नहीं मानती।

—बंबई ब्यूरो

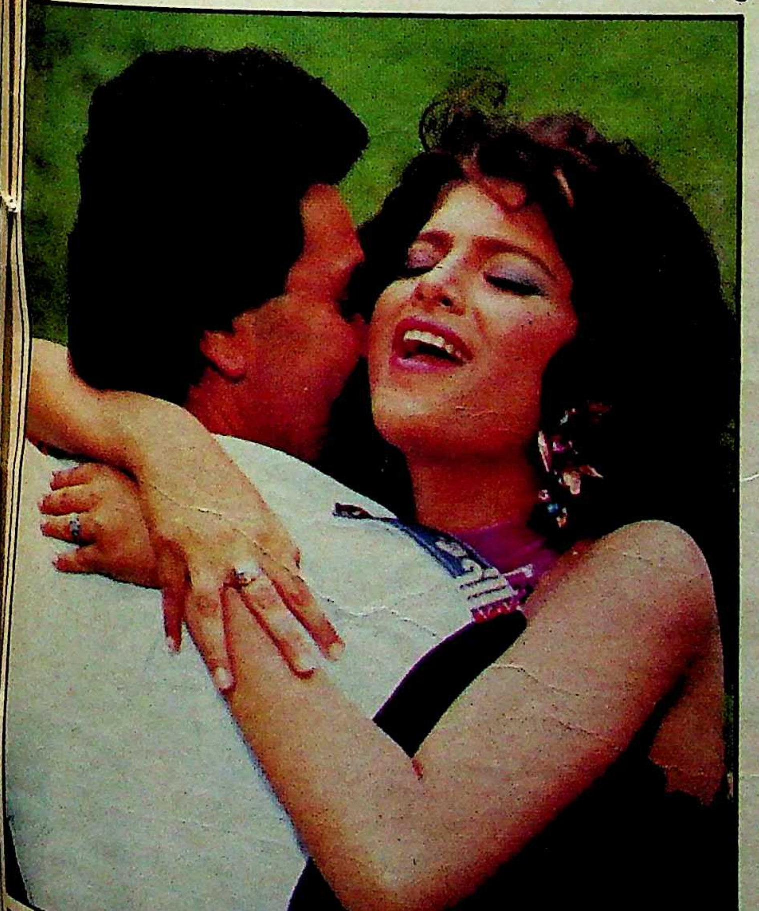

पहला-पहला साथ: सोनम और ऋषि कपूर फिल्म 'विजय' में

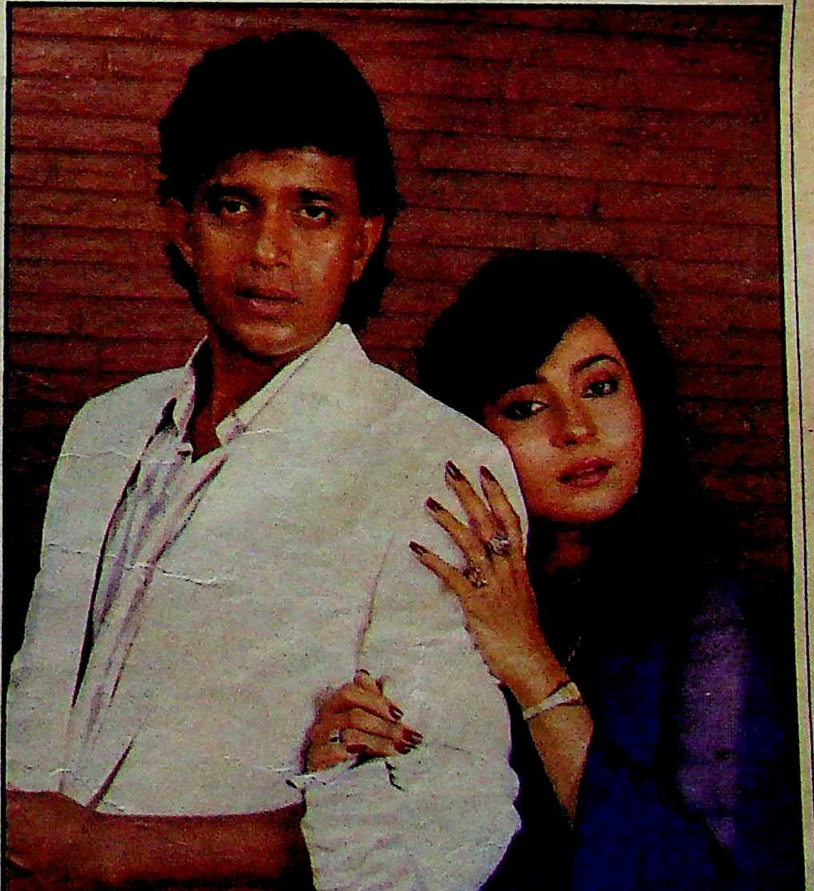

नयी शुरुआत: मिथुन चक्रवर्ती और सुजाता मेहता फिल्म 'सरपरस्त' में

जून द्वितीय अंक

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

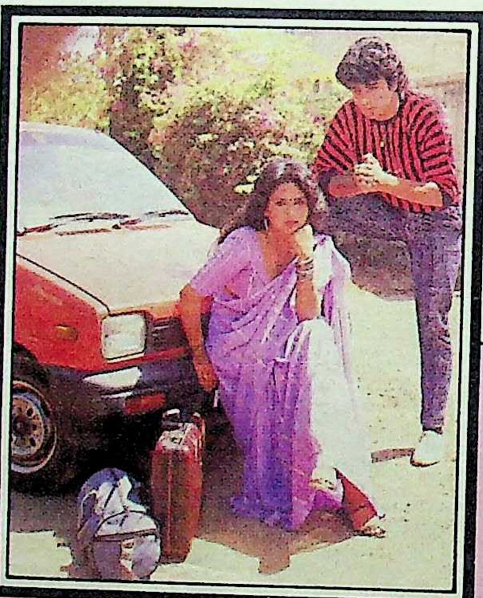

विशिष्ट रचनाएं
विशिष्ट रचनाकार

विशिष्ट लेख :

- बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने से पहले
- झूठी तारीफ करना आपकी भी आदत तो नहीं ?
- कामकाजी महिला और नौकरी के दांव-पेंच
- एक मां के मन की बात
- क्या आपकी सहेली आपसे दूर चली गयी है ?
- परिवार एक टीम है
- मुझे बेटा नहीं चाहिए
- जरूरत है एक महिला कार्टूनिस्ट की
- डाक्टर मेरा बच्चा ठीक तो होगा ?
- घरवाली तेरे रूप अनेक

आवरण कथा :

शादी करके क्यों पछताते हैं लोग ?

विवाह के बाद
अपने वैवाहिक जीवन से
संतुष्ट लोग बहुत कम मिलेंगे।
अधिकांश को कोई न कोई
असंतोष या पछतावा
जरूर होता है।
ऐसा क्यों होता है
और असंतोष की स्थिति से कैसे
उबरा जा सकता है ?

अन्य आकर्षण

- मेरी सुहागरात : सुहागरात दिन में बदल गयी
- सौन्दर्य : तनिये, घूमिये और सुडौल रहिये
- हवा कुंवारी है : जिन्दगी हॉस्टल की
- व्यंजन : स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल व्यंजन
- कहानी : आखिरी सौगात/ मालती जोशी
- फिल्म : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कमल हासन पर विशेष रचना

साथ ही अन्य सभी स्थाई स्तंभ

साक्षात्कार/सोनम

मैं ग्लैमर नहीं, प्रतिभा के बल पर टिकी हूं

माया : ***तुम्हारी अभी तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन तुमने सभी फिल्म अभिनेत्रियों से ज्यादा फिल्में साइन कर ली हैं, वह भी सिर्फ एक वर्ष के भीतर। क्या अजीब-सा नहीं लगता तुम्हें?***

सोनम : क्यों? अजीब-सा क्यों लगेगा? मैं किसी के पास फिल्में साइन करने नहीं जाती, लोग आफर लेकर खुद आते हैं मेरे पास। क्या घर आयी लक्ष्मी को लौटा देना आपको भला लगेगा?

माया : ***लेकिन अंग-प्रदर्शन या ग्लैमर के बल पर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा?***

सोनम : लगता है, दूसरे पत्रकारों की तरह आप भी बहक गयी हैं। मुझे ये फिल्में टैलेंट के बल पर मिली हैं।

माया : ***१५ वर्ष की उम्र में कितना टैलेंट आ जाता है?***

सोनम : जितना आना चाहिए। (कुछ रुककर) यश जी (यश चोपड़ा) से लेकर देव साब (देव आनंद) तक सारी जमात बेवकूफ नहीं है कि वे मुझे सिर्फ इसलिए साइन कर रहे हैं कि मैं टू-पीस पहनने के लिए तैयार रहती हूं। सिर्फ ग्लैमर या सेक्स प्रदर्शन के लिए उन्हे मुझे साइन करना होता, तो फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसी लड़कियां हैं कि इतने बड़े आफर के लिए वे कुछ भी न पहनने के लिए तैयार हो जायेंगी।

माया : ***और तुम?***

सोनम : मैंने आपको अपनी सीमा—टू पीस बिकनी की बतला दी, वह भी तब जब कहानी व सिचुएशंस की मांग हो।

माया : ***तुम तो पढ़ने में हमेशा जी चुराती रही, फिर यह कहानी और सिचुएशंस को कैसे समझ पाती हो?***

सोनम : पढ़ाई से मतलब स्कूल के नीरस कोर्स से दिल चुराना था, कहानी-उपन्यासों से नहीं। फिल्म भी तो कहानी और उपन्यास पर ही बनती है। फिर काम करते-करते सब कुछ समझ में आ जाता है, यहां तक कि आदमियों को भी हैंडिल करना (जोरों से हंसने लगती है)।

माया : ***इतनी छोटी-सी उम्र में दो-दो, तीन-तीन शिफ्ट में काम करने में थकावट नहीं आती, जबकि तुम्हारे ये दिन खेलने-कूदने के हैं!***

सोनम : जब ५०-६० वर्ष के हीरो लोग तीन-तीन शिफ्टों में काम करते नहीं थकते, तो मुझे तो चार-शिफ्टें ही करनी पड़ती हैं (हंसती है)।

माया : ***तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के ५० करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हुए हैं। अगर एक भी फिल्म फ्लाप हो गयी, तो कई प्रोड्यूसर तबाह हो जायेंगे।***

सोनम : मैं कोई रेसकोर्स का घोड़ा नहीं, जो मेरे ऊपर इतनी भारी रकम लगा दी गयी है। निर्माता, फायनेंसर तथा डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के पूरे सेटअप पर रुपए लगाता है, अकेली सोनम या गोविंदा पर नहीं। (तुनक कर) आप ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरी कोई फिल्म फ्लाप हो जाये तो...आपको तो उलटे मुझे शुभकामनाएं देनी चाहिए कि मेरी सारी फिल्में सुपर हिट हों।

माया : ***तुम अपनी उम्र से दुगुने और तिगुने बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही हो। उम्र का यह अंतर परेशानी नहीं पैदा करता?***

सोनम : दक्षिण में तो कई अभिनेत्रियों ने अपने दादा-नाना की उम्र वाले अभिनेताओं के साथ रोमांटिक लीड की भूमिकाएं कीं और उनमें वे काफी स्वाभाविक लगीं। आज वे टाप पर हैं। (कुछ रुककर सोचते हुए) उम्र का अहसास तो स्टूडियो के बाहर ही होता है। मेकअप कर जब हम कैमरे के सामने पहुच जाते हैं, तो हम सिर्फ फिल्म के किरदार भर रह जाते हैं।

माया : ***जो फिल्में अभी सेट पर हैं, उनमें तुम्हारी भूमिकाएं कैसी हैं? क्या इनसे एक विशेष इमेज बन जाने का खतरा तो नहीं है?***

सोनम : बिलकुल नहीं। किसी फिल्म में मैं गांव की लड़की हूं, तो किसी में पाकेटमार, किसी में वेश्या, तो किसी में माड गर्ल। तरह-तरह की भूमिकाएं होने के कारण इमेज में बंधने का सवाल ही नहीं उठता। रही फिल्मों की बात, तो सभी बड़े बैनर की हैं। जाने-माने निर्देशकों के साथ काम करने तथा बड़े निर्माताओं की फिल्में होने के कारण मेरा कैरियर चमकेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

माया : ***फिल्में साइन करते समय किन-किन बातों पर ध्यान रखती हो।***

सोनम : बड़ा बैनर, बड़े स्टार, बड़ा सेट अप, साथ ही मेरी भूमिका प्रथम लीड में हो। कहानी के बारे में ज्यादा नहीं सोचती।

माया : ***क्यों? कहानी तो फिल्म की जान होती है?***

सोनम : जब सारा कुछ बड़ा होगा, तो निश्चय ही वे बेहतरीन कहानी पर ही फिल्म बनायेंगे।

माया : ***दूसरी अभिनेत्रियों के मुकाबले जिस तरह से तुम्हें फिल्में मिलती जा रही हैं, इसे तुम तकदीर का चमत्कार कहोगी या मेहनत, निष्ठा और लगन का परिणाम?***

सोनम : दोनों। यों मैं तकदीर में बहुत विश्वास करती हूं। फीरोज खान ने जब मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, तो बोले—'देखना, यह लड़की एक दिन बहुत आगे जायेगी।' यही बात रोशन तनेजा ने भी ऐक्टिंग की ट्रेनिंग देते समय कही थी। लेकिन यह भी सही है कि फिल्म-निर्माता फिल्मों में मेरी परफारमेंस देख कर ही मुझे आफर दे रहे हैं। वरना ज्यादातर लोग नये कलाकार को साइन करके भी उसकी पहली फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार करते हैं तब शूटिंग करते हैं। इस मामले में मैं तकदीरवाली हूं।

—बंबई ब्यूरो

साक्षात्कार/**सुजाता मेहता**

मैं एक विशेष इमेज में बंधना नहीं चाहती

माया: *जब कलाकार की कोई फिल्म हिट होती है, तो उसके पास फिल्मों की भीड़ लग जाती है। आपकी 'प्रतिघात' तो सुपर हिट हुई थी, फिर भी आपके पास फिल्में बहुत कम हैं?*

सुजाता: ऐसा तो नहीं। मैं इस समय बीआर चोपड़ा की 'सरपरस्त', रमेश सिप्पी की 'जमीन', सोहन लाल कंवर की 'तड़प' विक्रम सिंह देवल तथा पद्मालय की भी एक-एक फिल्म कर रही हूं। इनके अलावा मेरे पास कुछ और भी फिल्में हैं।

माया: *लेकिन इन फिल्मों की नायिकाएं तो कोई और हैं?*

सुजाता: मैं सिर्फ रोमांटिक लीड वाली भूमिकाएं नहीं चाहती, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मैं आंख मूंद कर भी फिल्में साइन नहीं करना चाहती—कम फिल्में, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाएं। मैं इस भेडचाल का 'पार्ट' नहीं बनना चाहती।

माया: *लेकिन भेड़चालवाले लोगों के साथ आप काम तो कर ही रही हैं।*

सुजाता: क्यों, कीचड़ में कमल नहीं उगता क्या? इसी भेड़चाल वाली फिल्म इंडस्ट्री में चोपड़ा साहब या रमेश सिप्पी, जेपी दत्त, सोहनलाल कंवर जैसे निर्माता-निर्देशक भी तो हैं। मैं इंडस्ट्री को 'कंडेम' नहीं करना चाहती।

माया: *जब 'प्रतिघात' प्रदर्शित हुई या 'खानदान' अथवा 'श्रीकांत' टीवी सीरियल दिखलाये गये, तो लोगों ने मान लिया कि एक बेहतरीन अभिनेत्री का जन्म हुआ है, लेकिन आप तो उन कार्मशियल फिल्मों में जुट गयीं, जहां कलात्मकता का नामोनिशान नहीं।*

सुजाता: यह तो आपके ही प्रथम सवाल का मेरा जवाब हो गया! (हंसती है) 'प्रतिघात' और 'श्रीकांत' की सफलता के बाद कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन उनके आफर में मुझे दम नहीं लगा न कहानी में, न भूमिकाओं में, सो मैंने मना कर दिया। बेहतरीन भूमिकाओं वाली फिल्मों का इंतजार करना कहीं ज्यादा ठीक लगा।

माया: *आप जानी-मानी माडल तथा मराठा रंगमंच की अभिनेत्री रहीं, लेकिन शुरू में आपने कई आफर ठुकरा क्यों दिये?*

सुजाता: सोहन लाल कंवर 'खानदान' में मेरा अभिनय देख कर प्रभावित हुए थे, उन्होंने मुझे लेकर एक फिल्म की योजना बनायी, लेकिन तब मैंने इस लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, फिर वह नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में काम करूं। 'प्रतिघात' के निर्देशक एन चंद्रा ने भी 'खानदान' देखी थी, उन्होंने जब फिल्म में मुझे लेने की बात की, तो राजबब्बर ने भी उन्हें कहा, "आप इस लड़की को जरूर लीजिए, इसने 'चीत्कार' नाटक में लाजवाब अभिनय किया है।" 'श्रीकांत' जब शुरू हुआ, तो राजश्री वालों ने 'प्रतिघात' में काम करने का आफर दिया। फिल्मी कहानी काफी अच्छी लगी, मैंने तुरंत 'हां' कर दी।

माया: *'प्रतिघात' में आपको सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र करने का दृश्य था। आपने कैसे किया उसे?*

सुजाता: वह दृश्य एक जूनियर आर्टिस्ट पर फिल्माया गया था।

माया: *'खानदान', 'श्रीकांत', तथा 'प्रतिघात' ने आपको भारतीय नारी की इमेज दी थी, क्या उसे तोड़ने के लिए ही आपने फिल्मी पत्रिकाओं के लिए ग्लैमरस चित्र खिंचवाये, जैसा कि 'बुनियाद' की अनीता कंवर ने किया था।*

सुजाता: मुझे उनका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो सभी तरह के पोज पत्रिकाओं के लिए देती रही हूं। जिस तरह की रचनाएं वे छापते हैं, उसी तरह के मेरे चित्र लेते हैं। हां, मैं एक विशेष इमेज में बंधना जरूर नहीं चाहती, इसीलिए फिल्मों का चुनाव करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान रखती हूं।

माया: *आज के नये कलाकार 'इमेज' के नाम से बिदकते क्यों हैं? शबाना आजमी और स्मिता पाटील तभी तक टाप पर थीं, जब तक वे भारतीय नारी की इमेज में या कलात्मक फिल्मों से जुड़ी रहीं। इमेज को तोड़ते ही, वे कहीं की नहीं रहीं।*

सुजाता: नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे विचार से उन्होंने अपनी उस इमेज को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि कार्मशियल फिल्मों में भी वे सफल रहीं। 'थोड़ी सी बेवफाई' क्या कार्मशियल फिल्म नहीं थी शबाना की? रही मेरी बात, तो मैं एक तरह से प्रयोग कर रही हू कि कौन-सी इमेज बनाऊं? बनाऊं भी कि नहीं। अब 'प्रतिघात' जैसी फिल्में मेरे लिए कौन बार-बार बनायेगा? एक इमेज के बल पर मैं फिल्म इंडस्ट्री में कितने दिन 'सरवाइव' कर सकती हूं भला? यों मैं एक 'लव-स्टोरी' वाली फिल्म करना चाहती हूं।

माया: *क्या आपको राजेश खन्ना की 'जय शिव शंकर', शशि कपूर की 'अजूबा' तथा 'शेरा-शमशेरा' से हटाया नहीं गया?*

सुजाता: ओह! (जोर से हंसते हुए) 'जय शिव शंकर' में मुझे जो भूमिका दी जा रही थी, उसकी बजाय मैं दूसरी भूमिका चाहती थी। फिर यह उनका घरेलू (राजेश खन्ना-डिंपल) मामला था। अंत में वह भूमिका डिंपल को दे दी गयी। 'शेरा-शमशेरा' के लिए मेरी जो तारीखें वे लोग चाहते थे, वे रमेश सिप्पी के पास पहले से ही बुक थीं। अब मैं एक के फायदे के लिए दूसरे के साथ किये गये कमिटमेंट को तोड़ तो नहीं सकती थी। रही बात 'अजूबा' की, तो वह इंडो-रशियन कंबाइन प्रोजेक्ट के तहत बननी थी, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ। हां, शशि कपूर जरूर चाहते थे कि मैं यह फिल्म करूं।

माया: *फिल्मों में व्यस्त हो जाने पर क्या आप टीवी सीरियल और रंगमंच छोड़ देंगी?*

सुजाता: सीरियलों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन रंगमंच नहीं छोड़ूंगी। फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार की कैरियर जिंदगी बड़ी सीमित होती है, लेकिन रंगमंच पर ऐसा नहीं होता। अब मेरे नाटक 'चीत्कार' को ही देखिए, पिछले चार वर्षों में इसके लगभग ३०० शो हो चुके हैं, फिर भी इसकी मांग काफी है। 'चीत्कार' के निदेशक लतेश शाह के निर्देशन में बने एक सीरियल 'यस सर' में मैंने शफी इनामदार के साथ भी काम किया है।

—बंबई ब्यूरो

साक्षात्कार/बासु भट्टाचार्य

'वसुधैव' का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना है

निर्माता-निर्देशक बासु भट्टाचार्य अगर राजनीतिज्ञ होते, तो बड़े-बड़े दिग्गज उनका लोहा मानते नहीं अघाते। अपने तर्क-कुशल संवादों द्वारा वह घुटे हुए लोगों को भी चित्त कर देते हैं, इसीलिए व्यावसायिक खिड़की पर सिर्फ एक फिल्म (अनुभव) की सफलता के बल पर वह फिल्म इंडस्ट्री में पिछले तीन दशकों से छाये हुए हैं। पहले स्व० विमल राय के सहायक फिर दामाद बासु भट्टाचार्य ने (स्व०) शैलेंद्र की फिल्म 'तीसरी कसम' में राज कपूर और वहीदा रहमान को अपनी शैली में निर्देशित किया। उसके बाद कला फिल्मों की तरफ मुड़ गये। 'आधे-अधूरे' से लेकर 'गृह-प्रवेश' तक तमाम बहुचर्चित फिल्में बनायीं, जिनमें से बहुत-सी (आविष्कार, गृह प्रवेश, डाकू आदि) बाक्स आफिस पर पिट गयीं और बहुत-सी (आधे-अधूरे, पत्थर, हमारा कल्लू, संगत आदि) सिनेमा हाल का दर्शन तक नहीं कर सकीं, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कभी भी समझौता नहीं किया और फिल्में अपनी शर्तों पर अपनी विचार धारा के अंतर्गत ही बनाते रहे। आपातकाल में उन्होंने अमृता प्रीतम के साथ मिलकर स्व० प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक अधूरी डाक्युमेंट्री फिल्म बनायी। उसके बाद वह एक लंबे अरसे तक विभिन्न सरकारी-गैरसरकारी फिल्म संगठनों से इस कदर जुड़े रहे कि उनका एक पांव दिल्ली में होता, तो दूसरा बंबई या बंगलोर या मद्रास में। अब वह दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहे हैं—'वसुधैव'। इसके कलाकार हैं—उनके पुत्र आदित्य भट्टाचार्य, संजना कपूर, नवीन निश्चल, बीना, मिलन मुखर्जी तथा मैरिली। मैरिली अमरीकी अभिनेत्री है, जिसे उन्होंने इस सीरियल के लिए विशेष रूप से बंबई बुलाया था। शशि कपूर की बेटी संजना पिता का घर छोड़कर एक लंबे अरसे तक आदित्य भट्टाचार्य के साथ उनके घर पर ही रही। बासु भट्टाचार्य का विशेष प्रिय विषय रहा है—दांपत्य जीवन का तनाव और टूटते हुए विवाहेतर संबंध। इस पर उन्होंने तीन फिल्में (अनुभव, आविष्कार तथा गृह प्रवेश) बना डाली—दो के नायक थे, संजीव कुमार और शर्मिला ठाकुर, एक के नायक राजेश खन्ना और दूसरे की नायिका थीं, तनूजा। यह इत्तफाक था कि जिस विषय पर फिल्में बनाकर वह चर्चित हुए, वही उनकी निजी जिंदगी में हादसा बनकर उजागर हुआ। उनके नये सीरियल 'वसुधैव' के बारे में 'माया' ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत हैं, बातचीत के प्रमुख अंश:

मैं भीड़ के पीछे कतई नहीं भागता: बासु

माया: *फिल्में बनाते-बनाते यह सीरियल बनाने का खयाल कैसे आ गया आपको?*

बासु: न तो मैं कभी खयाल करता हूं और न ही उस तरह से आता है, जैसा आप सोच या समझ रहे हैं। मैं इस तरह की बातों पर विश्वास भी नहीं करता कभी।

माया: *तो क्या आप भी इस क्षेत्र में इसलिए आ गये कि सत्यजित रे से लेकर बीआर चोपड़ा, रामानंद सागर या गुलजार, राजेश खन्ना और हेमामालिनी जैसे बड़े निर्माता-निर्देशक (हेमामालिनी 'नृत्य यात्रा' सीरियल बना रही हैं और राजेश खन्ना का सीरियल 'आधा सच आधा झूठ' दूरदर्शन पर दिखलाया जा रहा है) भी दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल बनाने लगे हैं?*

बासु: नहीं, मैं भीड़ के पीछे कतई नहीं भागता। दरअसल मुझे महसूस हुआ कि पत्र-पत्रिकाएं बहुत सारी अच्छी चीजें छापती हैं, लेकिन हर दर्शक उन्हें पढ़ नहीं पाता। लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से 'बेहतरीन' से उसका परिचय कराया जा सकता है। सिर्फ यही बात थी, जिसने मुझे सीरियल बनाने के लिए प्रेरित किया।

माया: *लेकिन इतनी देर से क्यों?*

बासु: इसलिए कि किसी विषय ने मुझे इतने दिनों बाद 'हांट' किया।

माया: *वह क्या विषय था, जिसने आपको इस तरह 'हांट' किया कि आप इतनी तेजी से सक्रिय हो गये?*

बासु: रिश्ता, जो हमें एक-दूसरे से बड़ी नजदीकी से जोड़ता है। यों मैं इसे एक और ढंग से भी कहना चाहूंगा—एक विशेष किस्म की जिंदगी जीने के कारण हम जितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से अलग भी होते जा रहे हैं। 'वसुधैव' का विषय मनुष्य को मनुष्य की वास्तविकता से जोड़ने पर आधारित है।

माया: *इसकी कुछ कहानी भी बतलाना चाहेंगे?*

बासु: पूरी नहीं, क्योंकि इस कथा को किसी और ने अपना (हथिया?) लिया तो? संक्षेप में—गांव में बचपन बिताने के बाद एक लड़का आगे की पढ़ाई के लिए शहर पहुंचता है, तो बड़ी जल्दी ग्रामीण संस्कृति और परंपरा पर शहरी आधुनिकता अपना दबदबा बना लेती है। फिर वह उस शहर को भी छोड़ कर, आगे की पढ़ाई के लिए, विदेश चला जाता है। अपनी प्रकृति से वह कुछ इस कदर कटता है कि सिवाय एक जगह से उखड़ कर, दूसरी जगह जमने, फिर वहां से उखड़ कर तीसरी जगह पलायन के कुछ भी नहीं रहता—उसके सामने एक ओर अपनों से बिछुड़ने पर उत्पन्न 'अनसर्टेंटी' (अनिश्चय) आ जाती है, तो दूसरी तरफ कुछ पाने का लोभ! सीरियल का एक सीन है—विदेश में उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। उखड़ने और पलायन के कारण उसके मन में आ गयी रिक्तता तथा अकेलेपन का उसे अहसास है। वह उसे ढांढ़स बंधाती है—"आप चिंता न करें, आपको ज्यादा दिन अकेले नहीं रहना पड़ेगा।" इस पर वह बोल पड़ता है, "यह सब तो ठीक है, लेकिन जिस जगह, जिस ज़मीन से आया हूं, मुझे वहां नौकरी क्यों नहीं मिली? मैं देखने-जानने के लिए कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन अपना घर हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता।" सो यह है वह रिश्ता जो एक को दूसरे से, अपनी जमीनें-अपने आप से कटने से रोकता है।

'वसुधैव' में संजना कपूर और आदित्य भट्टाचार्य

माया: *तो आप भी आम फिल्मी लोगों की तरह वही 'पूर्व अच्छा है, पश्चिम बुरा है' फार्मूले को अपना रहे हैं?*

बासु: नहीं, कतई नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हम एक ऐसी वर्ण संकर सभ्यता में जी रहे हैं, जो बुनियादी सचाई से कट गयी है। हम रिश्ता बनाने के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है। मैं इसी सचाई को 'वसुधैव' के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। रही बात 'पूर्व-पश्चिम' की, तो मैं अगर ऐसी संकीर्ण बातों को मानता, तो फिर इस सीरियल का नाम भला 'वसुधैव' क्यों रखता?

—प्रस्तुति: महादेव शर्मा एवं बंबई ब्यूरो

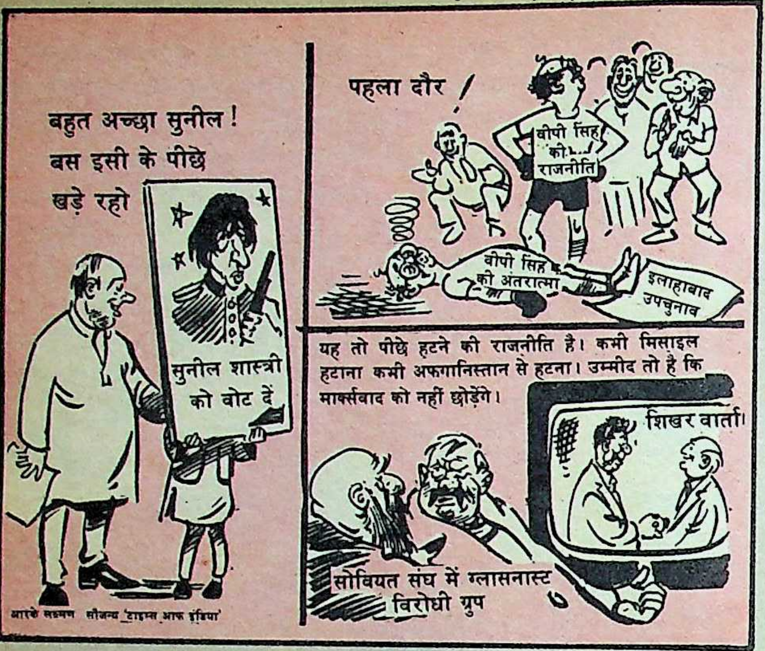
बहुत अच्छा सुनील !
बस इसी के पीछे
खड़े रहो
सुनील शास्त्री
को वोट दें
पहला दौर !
वीपी सिंह
की
राजनीति
वीपी सिंह
की अंतरात्मा
इलाहाबाद
उपचुनाव
यह तो पीछे हटने की राजनीति है। कभी मिसाइल हटाना कभी अफगानिस्तान से हटना। उम्मीद तो है कि मार्क्सवाद को नहीं छोड़ेंगे।
शिखर वार्ता।
सोवियत संघ में ग्लासनास्ट
विरोधी ग्रुप

आरके लक्ष्मण सौजन्य 'टाइम्स आफ इंडिया'

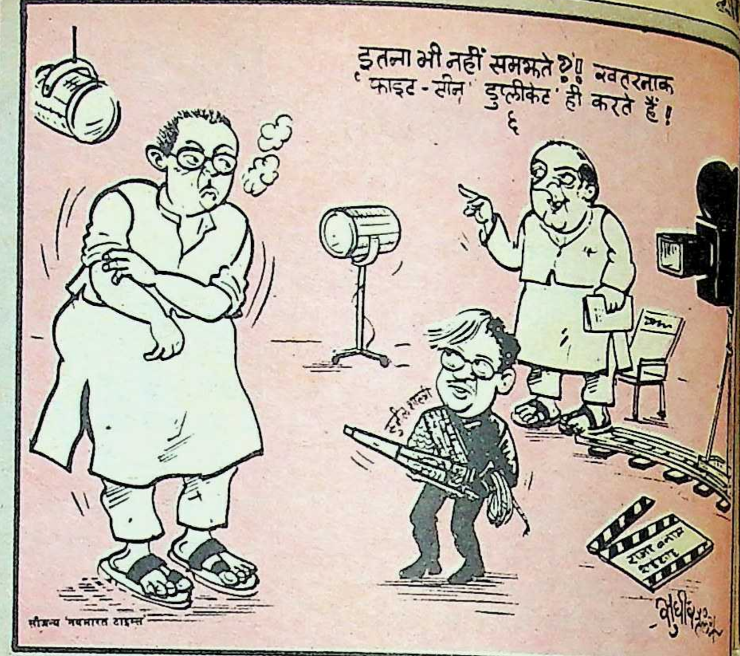
इतना भी नहीं समझते ?!! खतरनाक 'फाइट-सीन' डुप्लीकेट ही करते हैं !
डुप्लीकेट
राजा और
रंक
सुधीर तैलंग

सौजन्य 'नवभारत टाइम्स'

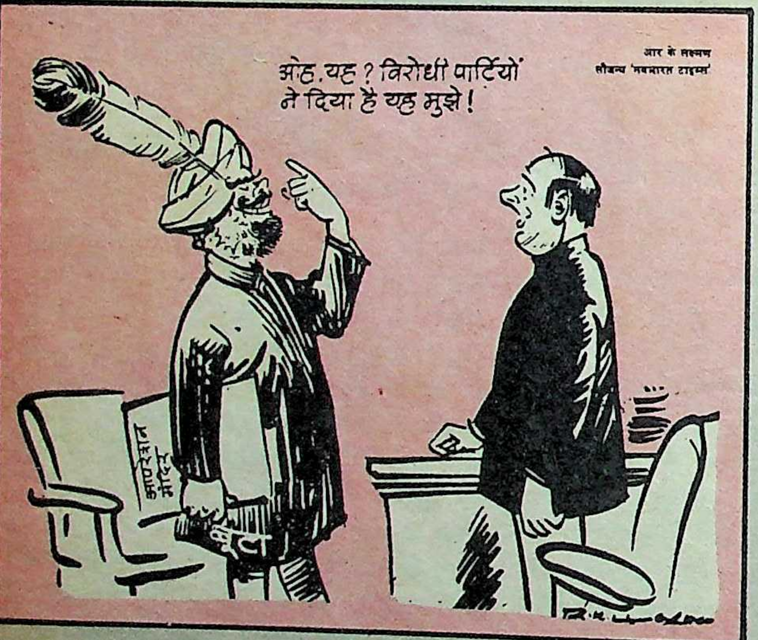
ओह, यह ? विरोधी पार्टियों
ने दिया है यह मुझे !
आपरेशन
मंदिर

आर के लक्ष्मण
सौजन्य 'नवभारत टाइम्स'

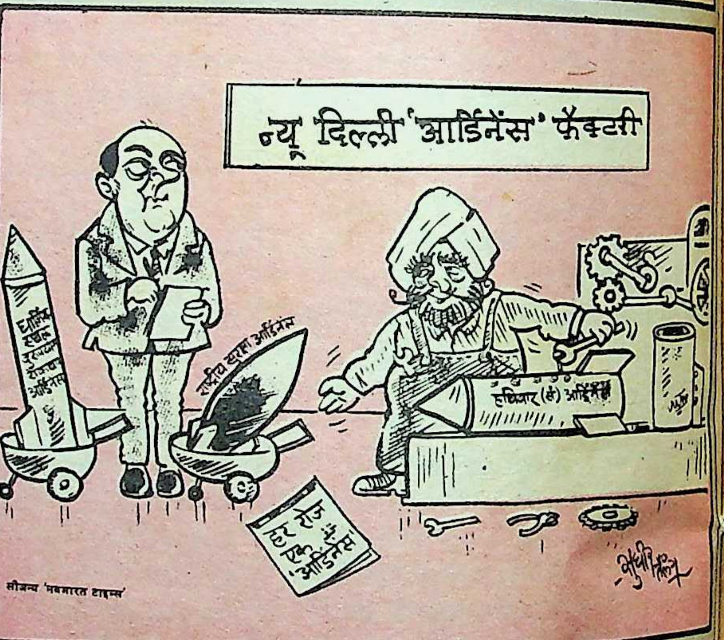
न्यू दिल्ली 'आर्डिनेंस' फैक्टरी
धार्मिक स्थल
आर्डिनेंस
राष्ट्रीय सुरक्षा आर्डिनेंस
हथियार (सं) आर्डिनेंस
हर रोज
एक
'आर्डिनेंस'
सुधीर तैलंग

सौजन्य 'नवभारत टाइम्स'

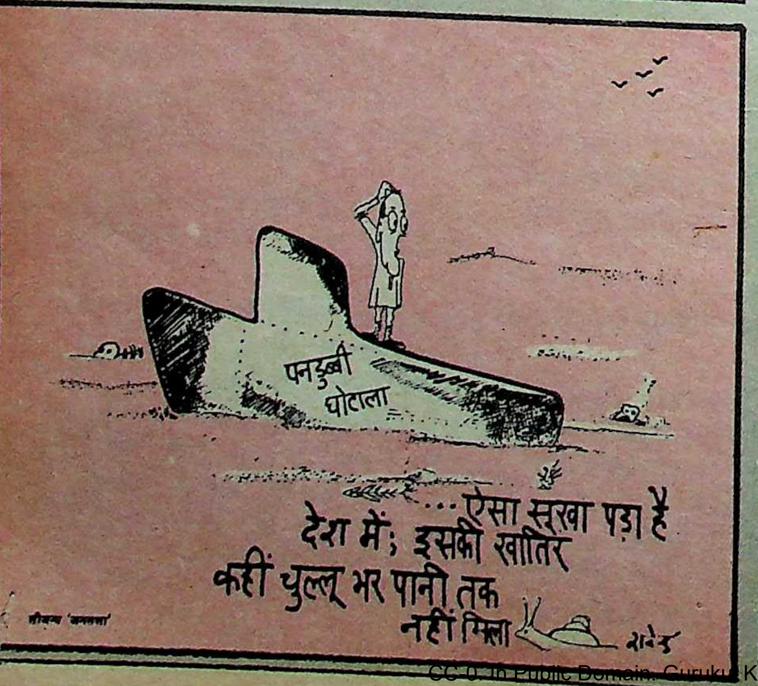
पनडुब्बी
घोटाला
...ऐसा सूखा पड़ा है
देश में; इसकी खातिर
कहीं चुल्लू भर पानी तक
नहीं मिला

सौजन्य 'जनसत्ता'

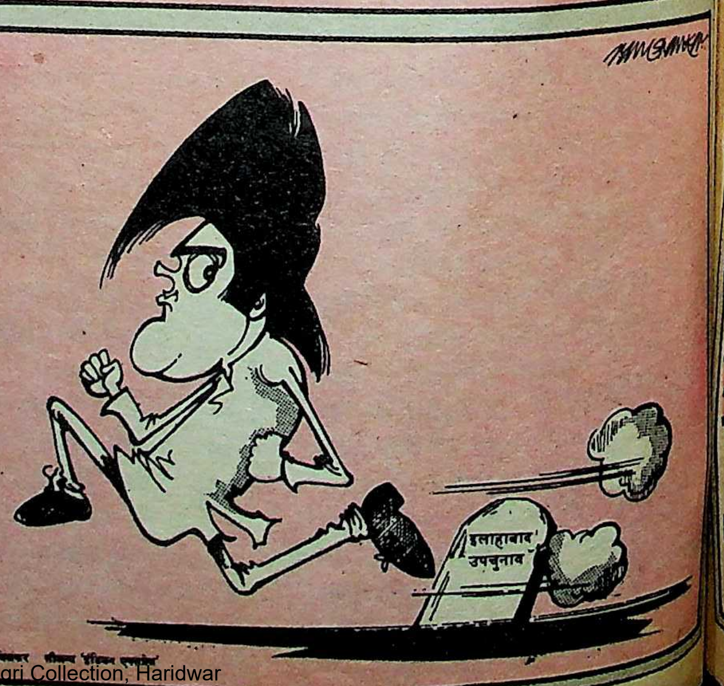
इलाहाबाद
उपचुनाव

रविशंकर सौजन्य 'इंडियन एक्सप्रेस'

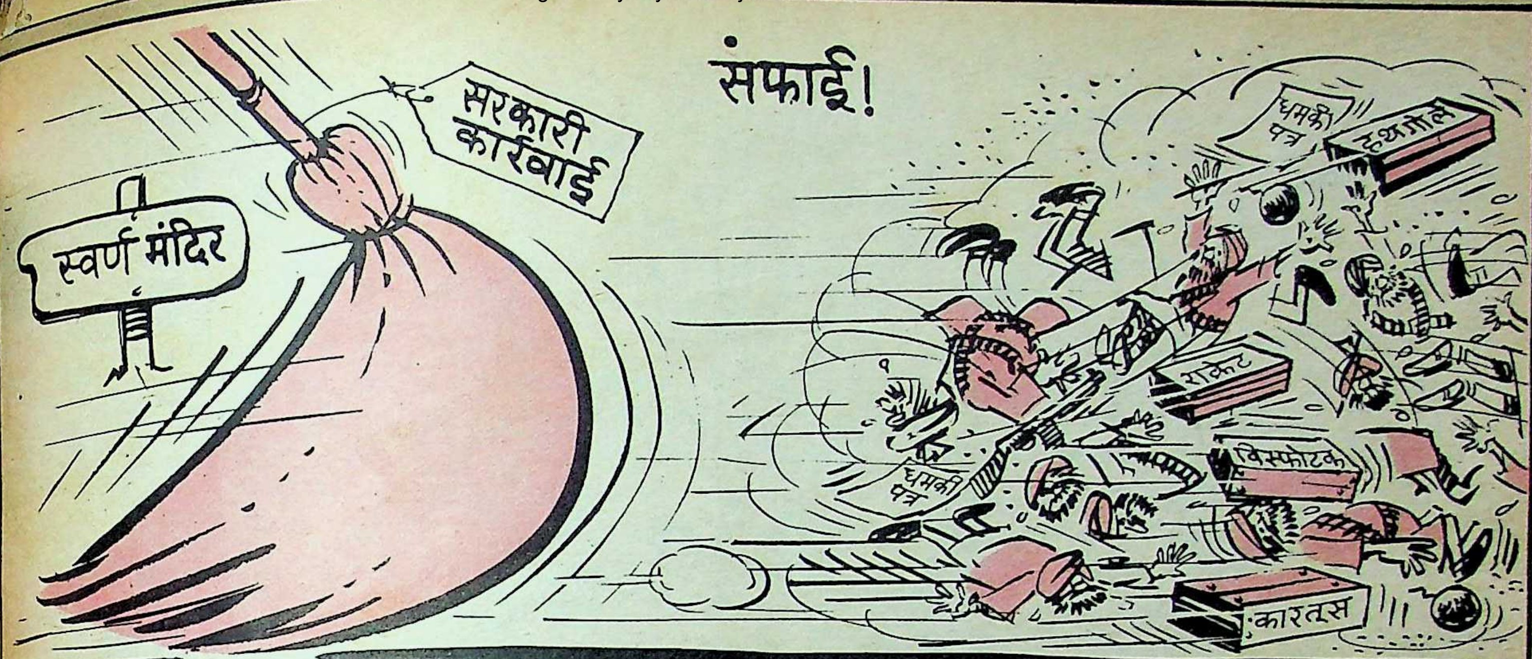
सफ़ाई!
सरकारी कार्रवाई
स्वर्ण मंदिर
धमकी पत्र
हथगोले
राकेट
धमकी पत्र
विस्फोटक
कारतूस

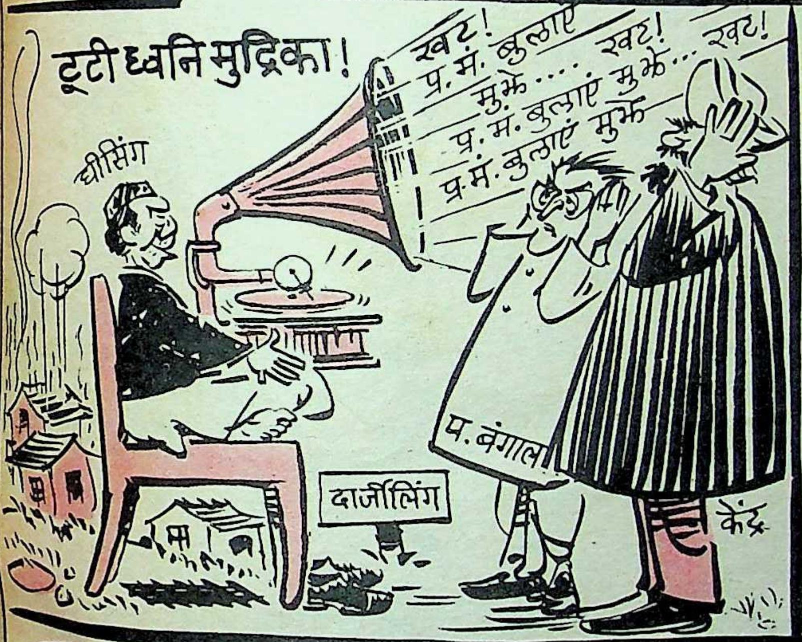
टूटी ध्वनि मुद्रिका!
खट! प्र.मं. बुलाएं मुझे.... खट! प्र.मं. बुलाएं मुझे... खट! प्र.मं. बुलाएं मुझे
घीसिंग
दार्जीलिंग
प. बंगाल
केंद्र

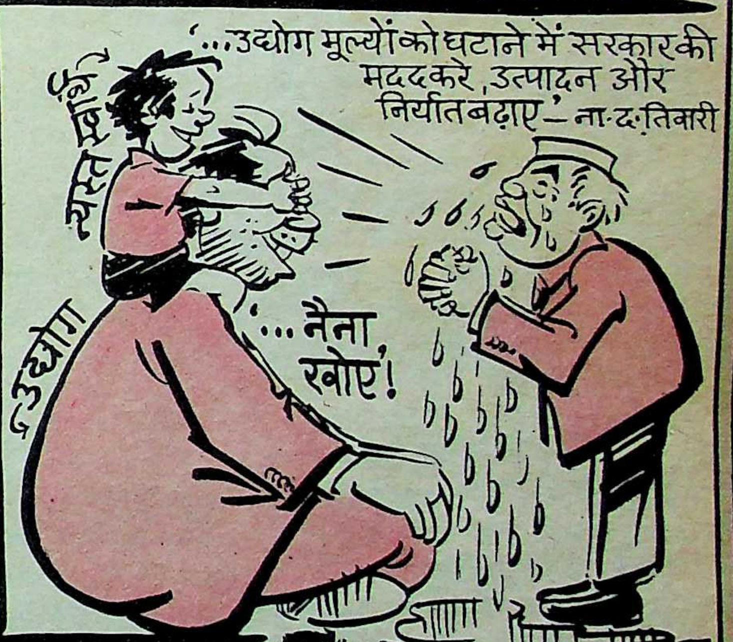
'...उद्योग मूल्यों को घटाने में सरकार की मदद करें, उत्पादन और निर्यात बढ़ाए' — ना.द. तिवारी
सस्ता माल
उद्योग
...नैना खोए!

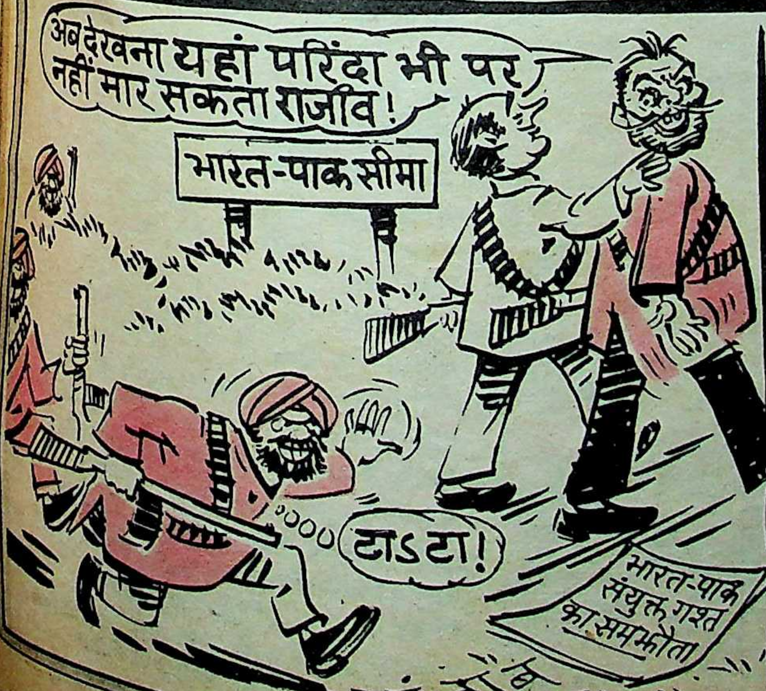
अब देखना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता राजीव!
भारत-पाक सीमा
टाऽटा!
भारत-पाक संयुक्त गश्त का समझौता
पंजाब

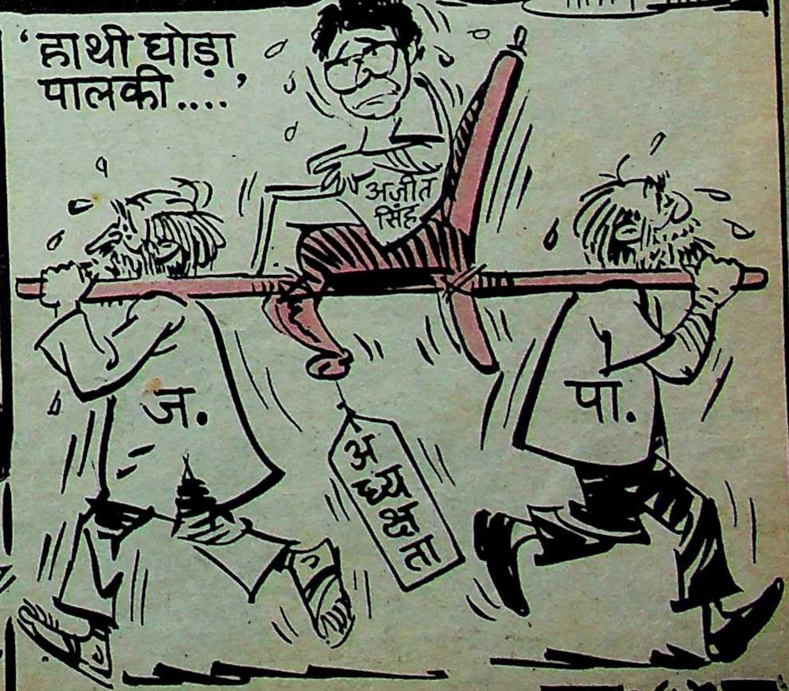
'हाथी घोड़ा, पालकी....'
अजीत सिंह
ज.
पा.
अध्यक्षता

आखिरकार इलाहाबाद में उपचुनाव हो ही रहा है। सभी सोच रहे हैं यह एक वीआईपी उपचुनाव है, हालांकि विपक्ष इसमें से 'आई' निकालने के चक्कर में है। शहर का स्त्री-वर्ग कुछ दिन बेहद बेताब रहा, उन्हें अमिताभ की आस थी। दूरदर्शन कार्यक्रम 'आजकल' में जिस तरह राजा, विनोद दुआ की बात काट कर अपना यकीन जाहिर कर रहे थे कि अमिताभ ही उपचुनाव में कांग्रेस-इ के प्रत्याशी होंगे, इससे स्त्री-समुदाय को और भी पक्का लग रहा था। कारण, राजा का यह कहना कि झूठ तो वह बोलते नहीं। उनके हिसाब से झूठे, बेईमान, मक्कार, दगाबाज सब अमिताभ हैं। फिर भी हैरानी का विषय है कि सारा महिला-वर्ग अमिताभ का समर्थक था। जी नहीं यह 'फैन एसोसिएशन' का मामला नहीं था। 'फैंस' का भी नहीं। यह एक सैद्धांतिक समर्थन था। हरिशंकर परसाई ने कई साल पहले जीवन का यह निचोड़ निकाला था कि औरत हमेशा पिटे हुए का साथ देती है। वह पीटने वाले से नफरत करती है फिर वह राजनीति का पीड़क हो या घर का। इस बीच अमिताभ बच्चन की पिटायी होती रही। उनकी मेडिकल गाड़ियां चलती रहीं, आंगन बाड़ी काम करती रही, हां वह खुद गैरहाजिर रहे। अमिताभ को राजनीति का इल्म नहीं। उन्हें चाहिए था कि चाहे दवा-गाड़ियां न चलवाते, कम-से-कम उनके पास खड़े होकर फोटो खिचवा लेते। सनद रहती, साख बनती। लेकिन अमिताभ का प्रचार-कार्य शुरू से गलत हाथों में रहा। इसके बावजूद जैसे उन्हें पिछली दफा शत-प्रतिशत महिला-वोट मिले थे, अब भी मिलते।

अमिताभ को प्रत्याशी न बनाने से राजा की रणनीति चौपट करने का, सत्तारूढ़ दल के पास एक प्रबल तरीका हाथ आया है। नामांकन-पत्र दाखिल करने की नाटकीयता के बाद राजा को चिढ़ाने, मुंह बिराने की बारी आयी। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव गुलाम नबी आजाद ने अपनी पूरी स्मार्टनेस से पूछा, "अब कहिए, अमिताभ तो बैठ गये, आप क्या खड़े ही रहेंगे?" राजा की अंतरात्मा ने कहा, "नहीं मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो अमिताभ के ईमान-धरम का चौकीदार था, वही नहीं आया, तो चौकीदारी किसकी करूं।" आजाद ने खिल्ली उड़ायी, "औरतों की तरह मुंह छुपा कर भाग रहे हैं राजा।" विपक्ष में हड़कंप मच गया। किसी तरह राजा की करवट बदलती अंतरात्मा को थपकी देकर सुलाया गया और राजा 'मर्द' बने, मैदान में आ डटे। वैसे सत्तारूढ़ दल को ध्यान रखना चाहिए कि राजा की ऐसी हालत न कर दे कि महिला-वोट राजा से हमदर्दी रखने लगें।

मुझे राजनीति में इतनी गहरी दिलचस्पी नहीं कि आगे का हाल भी सुनाऊं, पर जो बात चुभी वह यह कि ये कैसे मुहावरे इस्तेमाल में लाये गये। बेचारी औरत! उसे क्या मुंह छुपा कर भागना ही आता है। कायरता के सारे मुहावरे औरत को लेकर ही क्यों गढ़े गये हैं। सामाजिक मानस और संस्कार की पहचान भाषा से भी होती है। इस लिहाज से देखें, तो हमारी भाषा में असंख्य ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, जिनसे औरत कायरता का पर्याय है। बहरहाल यह लंबी बहस का विषय है। लेकिन पाठक गण नोट करें, इस उपचुनाव में दो महिला उम्मीदवार हैं, दोनों में से एक ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। चंद पुरुषों ने ही अपने नाम वापस लिये हैं। क्या राजा की जगह कोई महिला होती, तो सिर्फ इसलिए बैठ जाती कि वह महिला है।

मुहावरे किसी बात में लालित्य पैदा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर जिम्मेदार लोगों को महिला-वोट की भी फिक्र करनी होगी।

आजकल सर्वेक्षण का जमाना है। छोटे-छोटे टीवी सीरियलों की लोकप्रियता मापने तक के लिए सर्वेक्षण कराये जाते हैं, यह तो इलाहाबाद का उपचुनाव है। मैंने सोचा क्यों न महिला-मतदाताओं का एक सर्वेक्षण कर डालूं!

"बहन वोट किसे दोगी इस बार", सबसे पहले मैंने कृष्णा से पूछा।

कृष्णा मुहल्ले की महिलाओं की अगुआ है। दोपहर में उसी के घर बैठक जमती है, उसी के घर से गंगा-स्नान की साइत पूछी जाती है, उसी की मर्जी से किसी को अच्छा या बुरा कहा जाता है।

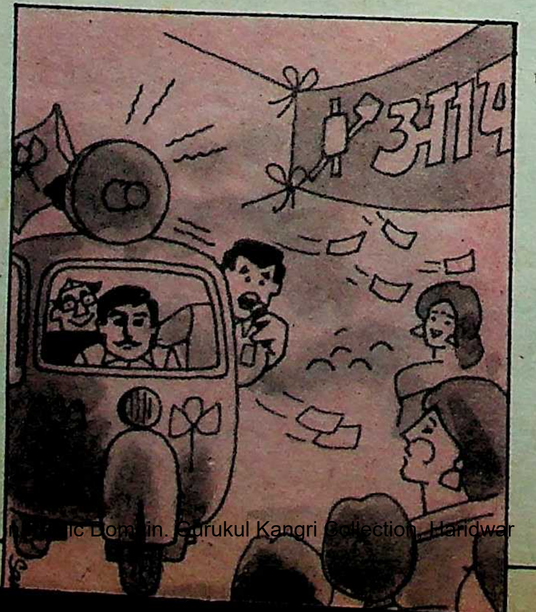

"ऐसे नहीं देंगे वोट। संभाल कर रख अंटी में।"

"क्यों?"

"मजाक लगा है क्या? पहले हमारे नल में पानी आये, गली की नाली साफ हो, चौराहे की बत्ती जले, राशन में अच्छा गेहूं मिले, तब हम देंगे वोट।"

मैंने उनकी लड़की माधुरी से पूछा, "किसे दोगी वोट?"

माधुरी एक स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल शहर के अंदर ही एक निर्जन सी सड़क पर पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते स्कूल से लौटते हुए उसके गले से सोने की चेन छिनी थी। वह उसी दहशत में रहती है।

"पहले शहर की सड़कें सुरक्षित हों, हमलोग सही-सलामत चल-फिर तो सकें, तब देंगे वोट।"

मोहन हलवाई की गर्भवती पत्नी दुलारी अपने पति के साथ-साथ दुकान का पूरा काम संभालती है। रोज सुबह जब मैं कालेज जाती हूं, उसे कढ़ाह भर दूध में कौंचा चलाते देखती हूं और सोचती हूं जाने कब यह दूध गाढ़ा होगा, कब खोया निकलेगा। पर दोपहर तक जब मैं वापस आती हूं, बढ़िया स्वादिष्ट खोया बन चुका होता है और दुलारी कृष्णा के घर जाने की तैयारी कर रही होती है।

"तुम किसे दोगी वोट, राजा को या रंक को?"

"ईंधन का दाम घटे तो वोट दें। चीनी महंगी होती जाती है, दूध महंगा होता जाता है, हम लोगन का वोट किसी को ना मिली।"

पहले ही चरण में सर्वेक्षण जाम हो रहा था। मैंने कालेज की ओर कलम की। अपनी साथी प्राध्यापकों से पूछा, "वोट देने जाओगी?"

"पहले हमारे कालेज को पक्का करें, कच्चे कालेज में काम करते-करते अपना तो मनोबल ही कच्चा हो चला है।" सबने एक साथ कहा।

इससे एक बात जोरों से जाहिर हुई कि महिला-वोट आज भी ठोस काम से संबद्ध हैं। काम और परिणाम लेकर सामने आइये और वोट ले जाइये। महिला-वोट हर बार किसी भी चुनाव में हार-जीत का फैसला करते हैं, इस बार भी करेंगे। स्त्रियां इस बात से प्रभावित नहीं होतीं कि कौन नेता, किसके समर्थन में कितनी बार सरकारी विमान से आया और गया, किसने कितने बड़े वायदे किये, किसने कितनी तालियां बजवायीं। उन्हें कार्य और प्रमाण चाहिए, नहीं तो वे सविनय अवज्ञा करती रहेंगी।

—ममता कालिया

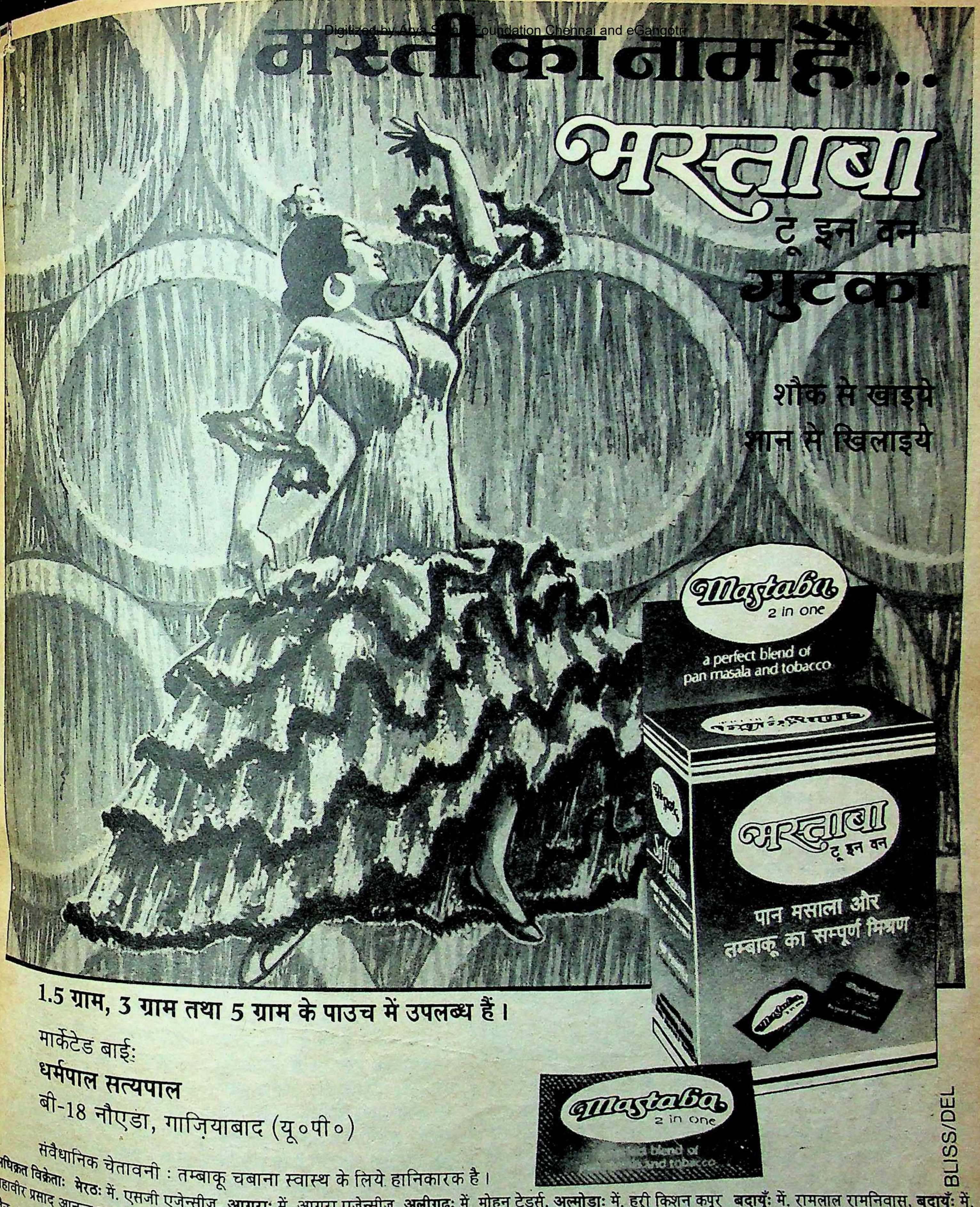
मस्ती का नाम है...
मस्ताबा
टू इन वन
गुटका
शौक से खाइये
शान से खिलाइये
Mastaba
2 in one
a perfect blend of
pan masala and tobacco
मस्ताबा
टू इन वन
पान मसाला और
तम्बाकू का सम्पूर्ण मिश्रण
Saffron
Mastaba
2 in one
blend of
and tobacco
BLISS/DEL

1.5 ग्राम, 3 ग्राम तथा 5 ग्राम के पाउच में उपलब्ध हैं।

मार्केटेड बाई:

धर्मपाल सत्यपाल

बी-18 नौएडा, गाज़ियाबाद (यू०पी०)

संवैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

अधिकृत विक्रेता: मेरठः में. एसजी एजेन्सीज, **आगराः** में. आगरा एजेन्सीज़, **अलीगढ़ः** में. मोहन ट्रेडर्स, **अल्मोडाः** में. हरी किशन कपूर **बदायूँः** में. रामलाल रामनिवास, **बदायूँः** में. महावीर प्रसाद आनन्द प्रकाश, **चन्दौसीः** में. सुनिल कुमार मनोज कुमार, **बरेलीः** में. कृष्णा इन्टर प्राइजेज, **एटाः** में. सिंघल जर्दा हाउस, **फिरोजाबादः** में. पाण्डे राजा राम गुलाब चन्द जैन एण्ड सन्स, **हल्द्वानीः** में. कपूर टोबैको स्टोर, **हाथरसः** में. जे.सी. टोबैको एजन्सीज, **कासगंजः** में. त्रिवेणी बिजनेस कम्बाइन, **मथुराः** में. जैन एजेन्सीज **कानपुरः** में. बाजपेयी जनरल स्टोर, **पटनाः** में. एस.के. ट्रेडर्स, में. डी. लाल एण्ड सन्स (एजेन्सीज), **गोरखपुरः** में. बल्देव राम मोहन लाल, **अहमदाबादः** में. रूचि इन्टर प्राइजेज, **जैपुरः** में. शिवनाथ प्रसाद चौरसिया, **जोधपुरः** में. नरायन दास भाग चन्द, **कोटाः** में. अकुंर सुपारी स्टोर, **उदयपुरः** में. रतनलाल भंवर लाल जैन, **राजकोटः** में. दामजी राघव जी एण्ड कं., **सिलीगुड़ीः** में. बन्सल एजेन्सी, **सूरतः** में. शाह भरत कुमार अमृत लाल, **सुरेन्द्र नगरः** में. चिमन लाल भगवान जी एण्ड कं., **भावनगरः** में. साधना एजेन्सी, **धोराजीः** में. इब्राहिम ए. लतीफ, **जूनागढ़ः** में. मोहन लाल केशव दास एण्ड कं., **बरोड़ाः** में. हिन्द स्टोर्स, **हनुमानगढ़ः** में. भारतीय भुजिया मिष्ठान भण्डार, **दुबईः** में. मधुर स्टोर्स,

जियाउलहक

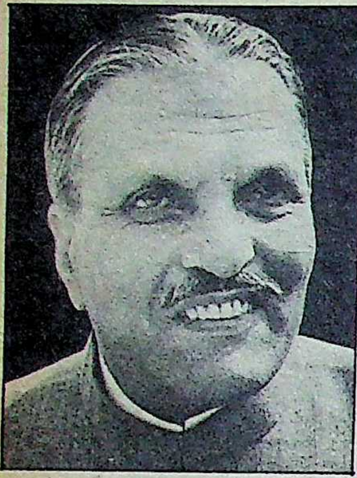

पिछले दस वर्ष ग्यारह महीने से लगातार नाटकीय फैसले लिये जाने और एक तानाशाह शासक के रूप में चर्चित पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउलहक का ताजा नाटक है जुनेजो-मंत्रिमंडल को बरखास्त करके ९० दिनों में चुनाव कराने की घोषणा। पर ऐसा लगता नहीं। सत्ता का भूखा शासक चुनाव कराकर अपनी कुरसी के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता। भुट्टो को फांसी देने से लेकर जुनेजो की बरखास्तगी तक की सारी घटनाएं गवाह हैं जियाउलहक की राजनीतिक चतुराई की। पाकिस्तान में जो हालात हैं, वे जिया के पक्ष में तो नहीं लगते। कूटनीति का खेल खेलनेवाले जिया ने यह फैसला तब लिया है, जब उन्हें खबर मिल गयी कि उनके खिलाफ बराबर जंग जारी रखनेवाली बेनज़ीर भुट्टो भविष्य में मां बननेवाली हैं और बहुत सक्रियता नहीं दिखा सकतीं।

विडंबना है कि मुस्लिम अणुबम की दुहाई देने वाले जनरल जिया को 'गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल अवार्ड फार पीस ऐंड कोआपरेशन' भी मिल चुका है।

"कभी झूठ नहीं बोलता," कहने वाले जिया अपने मुल्क की खातिर झूठ बोलने को झूठ बोलना नहीं कहते। जिया कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। उसे धर्म निरपेक्ष बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे पाकिस्तान ढह जायेगा। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि इससे विदेशी ताकतें पाकिस्तान को तोड़ देंगी। १२ अगस्त, १९२४ को जन्मे जिया शांति को बटन नहीं मानते कि उसके दबाने से शांति कायम हो जायेगी। शांति तो साइकल के हैंडिल की तरह है, जहां दोनों ओर संतुलन बनाये रखना जरूरी है।

जिया ने १९४१ में सेना में प्रवेश लिया। उन्होंने स्टाफ कालेज क्वेटा से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद १९६३ में अमरीका में सैन्य अध्ययन करते रहे। वह १९६४ में क्वेटा के स्टाफ कालेज में इंस्ट्रक्टर नियुक्त हुए। १९६९ में ब्रिगेडियर, १९७२ में मेजर जनरल, १९७६ में आर्म स्टाफ के प्रमुख और इसके अगले वर्ष चीफ मार्शल। ला प्रशासक बनने वाले जिया ने १६ सितंबर, १९७८ को सैनिक जोर पर अपने को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तानाशाह शासक के रूप में उनकी छवि तब और उभरी, जब दुनिया भर से आयी क्षमादान की अपीलों के बावजूद जिया ने १९७९ में भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया।

गोल्फ खेलने के शौकीन जिया का दिमाग कब क्या चाल चल जाये, कहा नहीं जा सकता।

कविता चौधरी

कविता चौधरी का नाम मीडिया के लिए नया नहीं है। यह अलग बात है कि उन्हें माडलिंग से ख्याति मिली है। वह भी 'सर्फ' की माडलिंग वाली इमेज से। 'सर्फ' की खरीदारी में ही समझदारी है कहनेवाली 'ललिताजी' उर्फ कविता चौधरी इन दिनों दूरदर्शन के परदे पर अपने सीरियल 'उड़ान' को लेकर चर्चा में हैं। 'सर्फ' के प्रचार माध्यम से घर-घर में पहचानी जाने वाली ललिताजी (कविता चौधरी) अब कल्याणी के रूप में एक निम्न मध्यम परिवारवाली जुझारू लड़की की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दो-जहद कर रही हैं। बेशक अपने उसी किरदार की वजह से वह दूरदर्शनी दर्शकों पर छायी हुई हैं।

अमृतसर में जन्मी कविता चौधरी को बचपन से अभिनय करने का शौक था। इस शौक को कैरियर के रूप में ढालने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में प्रवेश लिया। इसके बाद वह लगातार मंच और टीवी नाटकों से जुड़ी रहीं। भीमसेन की फिल्म 'तुम लौट आओ' में कविता चौधरी ने मुख्य भूमिका की थी। 'उड़ान' के पहले कविता कई विज्ञापन फिल्मों का निर्माण भी कर चुकी हैं। 'उड़ान' के निर्माण की पृष्ठभूमि में कविता ही रची-बसी हैं। जैसे पूरी कथा का ताना-बाना मानो उन्हीं के लिए बुना गया है। अभिनय से लेकर पटकथा, निर्देशन और परदे के पीछे का सारा काम कविता ने ही संभाला है। अभी तक 'उड़ान' की जितनी कड़ियां प्रदर्शित की गयी हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना बेजा न होगा कि कविता चौधरी में अभिनय से लेकर निर्देशन तक की अनंत संभावनाएं हैं। उनकी प्रतिभा कितनी कारगर सिद्ध होती है, यह तो समय ही बतायेगा।

रूसी मोदी

यदि पूछा जाये कि देश में सबसे ज्यादा वेतन और भत्ता पाने वाला कौन व्यक्ति है, तो शायद जवाब होगा टिस्को के चेयरमैन रूसी मोदी। रूसी मोदी को अमरीका की एक पत्रिका ने विश्व के बीस प्रमुख व्यावसायिक हस्तियों में माना है। सर होमी मोदी के तीन पुत्रों में सबसे बड़े रूसी मोदी ने हैरो में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कैंब्रिज यूनीवर्सिटी से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। 'बिजनेस इंडिया' ने १९८३ में उन्हें 'मैन आफ द ईयर' घोषित करते हुए लिखा था कि रूसी मोदी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसायी हैं और समाज में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। टेक्नालाजी के विकास के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत हैं।

एक प्रशासक होते हुए रूसी मोदी मजदूरों के बीच कित लोकप्रिय हैं, इसका एक ही उदाहर काफी होगा। उनके जन्म दिन प लगभग तीस हजार मजदूर सि इकट्ठे ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने रू मोदी को हाथी पर बिठाक जमशेदपुर में घुमाया भी। कहनेवा तो इसे नौटंकी और टिस्को द्वा प्रायोजित कहते हैं। पर टिस्को उनकी सहयोगी टिनप्लेट कंपनी और इंडिया ट्यूब कंपनी के पचास हजा से ज्यादा मजदूरों का जिस आदमी को समर्थन हो, उसे नौटंकी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इतना समर्थन वह भी श्रमशक्ति, जिसे मि जाये, वह राजनीतिक शक्ति तो बन ही जाता है। ऐसी श्रमशक्ति को संभालना आसान नहीं है। पर इसके बावजूद रूसी मोदी लोकप्रिय हैं, तो उसे उनका चमत्कार ही माना जायेगा। रूसी मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बिहार के राजनीतिज्ञों की नींद हराम हो गयी थी, क्योंकि रूसी मोदी बिहार के नेताओं को घास नहीं डालते थे, तभी तो उनका पांच साल का कार्यक्रम घटाने के लिए सरकार को अपने खास अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। रूसी मोदी टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी के दुबारा चेयरमैन नहीं हो सकते, इससे बिहार के नेता और अफसर खुश हो सकते हैं, पर रूसी मोदी ने मजदूरों के बीच जो अपनी इमेज खड़ी कर ली है—उसे धो-पोंछ कर साफ करना मुश्किल है।

—दिनेश

विश्व युवाछात्र आंदोलन

भारत की भूमिका

DELHI 14–16 MAY 1988
XIII WORLD
FE TIVAL OF YO AND S ENTS
ONAL PRE OMM

मुकुल वासनिक, दीप प्रज्ज्वलित करती हुई मारग्रेट अल्वा

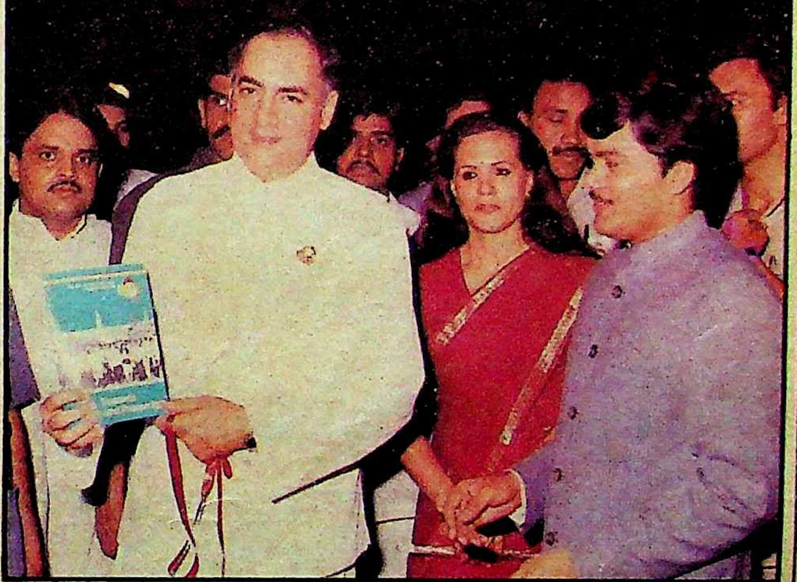

पुस्तक का विमोचन करते हुए राजीव गांधी। साथ में सोनिया और वासनिक

१९४७ में प्राग में जिस प्रथम युवा छात्र विश्व महोत्सव का गठन हुआ था, उसी के १३वें विश्व महोत्सव के संबंध में एशिया में पहली बार नयी दिल्ली में १४ से १६ मई तक दूसरी अंतरराष्ट्रीय तैयारी समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति की इस बैठक के संबंध में मास्को में फरवरी १९८७ में भारत के समस्त युवा-छात्र संगठनों से अपील जारी की गयी थी। भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष आनंद शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत बातचीत की थी। अक्तूबर १९८७ में अपना पद त्याग करने के पूर्व ही श्री शर्मा ने इस तैयारी समिति की बैठक को भारत में करने का दायित्व स्वीकारा था।

भारत को इस बैठक का स्थल चुने जाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि प्यांगयांग में महोत्सव के आयोजन को लेकर पश्चिमी देशों और समाजवादी देशों के युवा संगठनों में मतभेद था। समझौते के तौर पर यह तय हुआ कि दूसरी तैयारी समिति की बैठक न केवल तटस्थ और सर्वमान्य, बल्कि ऐसी जगह पर की जाये, जहां युवा संगठनों में बैठक करने की सक्षमता और सुविधा विद्यमान हो। और यह भारतीय युवा संगठनों के पास पर्याप्त मात्रा में थी। इसकी जानकारी युवा इंका द्वारा आयोजित गुट निरपेक्ष युवा कांफ्रेंस और नस्लवाद विरोधी युवा कांफ्रेंस की सफलता के बाद सर्वविदित थी। इसके अतिरिक्त पहली तैयारी समिति को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि भारत तीसरी दुनिया के युवा संगठनों के आंदोलन का नेता है।

नयी दिल्ली में हुई तैयारी समिति का उद्घाटन युवा मामलों की केंद्रीय राज्यमंत्री मारग्रेट अल्वा ने किया। इस बैठक में लगभग १०० अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। यद्यपि बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने निभायी, किंतु व्यापक भारतीय युवा-छात्र संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाकपा, माकपा और जनता पार्टी आदि के युवा संगठनों ने भी इसमें भाग लिया।

बैठक में १३वें युवा-छात्र विश्व महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा सुनिश्चित की गयी। विश्व महोत्सव के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, पर्यटन आदि के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गये। बैठक के दौरान इस दिशा निर्देश के अनुरूप व्यापक कार्यक्रम हेतु एक अस्थायी कार्यकारी दल का गठन किया गया, जिसमें २८ देशों व ६ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दल की पहली बैठक तैयारी समिति के समापन के तुरंत बाद हुई। इसकी दूसरी बैठक आगामी सितंबर में अल्जीरिया में होगी और तीसरी नवंबर में बर्लिन में होगी।

तीसरी अंतरराष्ट्रीय तैयारी बैठक का स्थान और तारीख भी इसी बैठक के दौरान सुनिश्चित की गयी। तीसरी अंतरराष्ट्रीय तैयारी समिति की बैठक बर्लिन में आगामी २५ से २७ नवंबर के दौरान होगी। नयी दिल्ली की इस बैठक में एक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता कोष का गठन किया गया।

महोत्सव के संबंध में शांति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद नस्लवाद विरोधी अभियान, मुक्ति संघर्षों में एकजुटता, सामाजिक, आर्थिक प्रगति, युवाओं-छात्रों के अधिकारों के उन्नयन का माहौल तैयार करने पर बल दिया गया।

तैयारी समिति की बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने समस्त प्रतिनिधियों के सम्मान में अपने आवास पर एक भोज का आयोजन किया। युवा इंका अध्यक्ष मुकुल वासनिक के अनुसार तैयारी समिति के सभी आयोजक बैठक की सफलता से अत्यधिक प्रसन्न हैं। कारण, कार्यक्रम के समस्त मुद्दों की अपील और विज्ञप्ति को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में शामिल समस्त प्रतिनिधियों की आम राय थी कि बैठक पूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुई। उदाहरण के तौर पर मुकुल वासनिक ने 'माया' को बताया कि सभा के अंत में जारी की गयी विज्ञप्ति पर विचार-विमर्श, जो प्रातः दस बजे प्रारंभ हुआ, वह पूरे दिन और रात चलने के उपरांत अगले दिन प्रातः ७ बजे समाप्त हुआ। श्री वासनिक का दावा है कि इस बैठक के बाद भारतीय युवा छात्र संगठनों की भूमिका महोत्सव आंदोलन के बीच उभर कर सामने आयेगी।

पूर्व युवा इंका अध्यक्ष आनंद शर्मा के अनुसार इस बैठक के सफल आयोजन ने एक बार फिर भारतीय युवा आंदोलन को विश्व युवा संगठनों के मध्य महत्वपूर्ण स्थान और स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही यह भी सिद्ध किया है कि हम विश्व युवा आंदोलन में एक महती भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर हैं।

—विशेष प्रतिनिधि

हेमामालिनी

न भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना अपनी पहचान बनाये रखने के लि हाल में एक नायाब तरीका खो निकाला है। वह तरीका है—शास्त्रीय नृत्य पर एक टीवी सीरियल बन का। १३ एपीसोडों वाले इस सीरि 'नृत्य यात्रा' की लेखिका, निर्मा निर्देशिका और अभिनेत्री वह खुद हैं। जब से एक पंखे तथा महारा राज्य लाटरी के लिए उन्होंने माडलि की, तब से वह अपने को एक अच्छ कमेंटेटर भी मानने लगी हैं। लेकि धर्म-पति धरम ने उन्हें यह समझा कि अपने ऊपर तुम कमेंट्री करोगी, तो अटपटा लगेगा। धर्म-पति की सला मानकर हेमामालिनी ने यह काम सौं हवेलीराम उर्फ आलोकनाथ को। वैसे हेमा ने उन्हें अपने साथ शास्त्रीय नृत्य करने का भी आफर दे रखा है। अब आलोकनाथ गोपीकृष्ण बनें या अमीन सयानी—यह प्रश्न उन्हें सता रहा है।

आलोकनाथ

मनीषा कोहली

घुंघरू और बंदूक

जब से डिपल कपाड़िया ने फिल्म 'महावीरा' में दस्यु सुंदरी का बाना पहन कर बंदूक हाथ में थामी है, तब से श्रीदेवी से लेकर श्रीप्रदा तक में दस्यु सुंदरी बनने की होड़-सी मच गयी है। जीनत अमान ने तो बंदूक थाम कर अपनी वापसी के लिए जोर-आजमाइश तक की। हेमा मालिनी ने भी 'मदर इंडिया' की नरगिस की तर्ज पर बंदूक थाम कर अपना शौक पूरा किया।

अब उन्हीं हेमा मालिनी ने जो बढ़ती उम्र के [illegible]टार रह सकीं,

मनीषा कोहली का नहला

यदि कोई किसी प्रतियोगिता में हा जाये, तो दुखी तो होगा ही, लेकि मनीषा कोहली वह लड़की हैं, जो हा को खुशी की तरह स्वीकार करत हैं—भले ही तर्ज हो अंगूर खट्टे बीआर चोपड़ा की 'अवाम' फिल्म नंबर दो की नायिका मनीषा कोहल 'मिस वर्ल्ड' के बजाय 'मिस एशिय चुनी गयीं, तो भी वह खुशी से उछल रहीं। वह घूम-घूम कर कहने ल "मुझे तो सचमुच बड़ी खुशी हुई 'मिस वर्ल्ड' न चुने जाने पर।

सियानी बिल्ली खंभा नोंचे वाली हावत न मानिए। 'मिस वर्ल्ड' नकर पूरे एक वर्ष तक मैं अनुबंध में ध जाती। ऐसे में मेरे फिल्मी कैरियर क्या होता? एक वर्ष में तो फिल्म ले भूल जाते। तब शादी और घर ही रे हिस्से में आता।"

फिल्मों से उम्मीद रखने वाली मनीषा की फिल्म 'अवाम' प्रदर्शित होते ही परदे से उतर गयी। अच्छा हुआ कि यह हादसा तब हुआ, जब वह दन में थीं। वरना उन्हें समझ में आता कि फिल्मी कैरियर का भविष्य क्या है? वैसे इधर उन पर विनोद खन्ना और जीतेंद्र मेहरबान हैं। पर मनीषा कहती हैं कि उन्हें इधर जो फिल्में मिल रही हैं, वे किसी की हरबानी से नहीं, बल्कि 'अवाम' तथा दूसरी फिल्मों में निभायी गयी उनकी भूमिकाओं के कारण। अब ऐसे में विनोद और जीतेंद्र जो चाहें, सोचा करें!

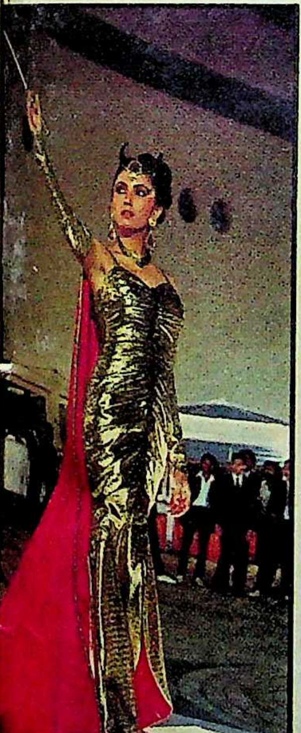

दीपा साही 'हीरो हीरालाल' में

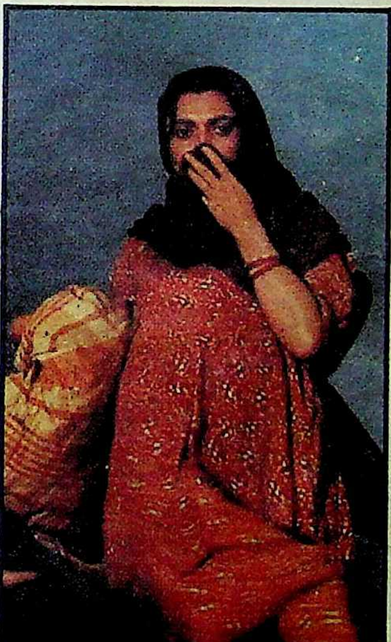

'तमस' की दीपा साही

रमो का आतंक, नहलानी का गम

बढ़िया फिल्म अभिनेत्रियां इस बात से बराबर परेशान रहती हैं कि नकी इमेज किसी एक खास भूमिका लिए न बन जाये। इधर 'तमस' की रमो उर्फ दीपा साही जब इस दौर से गुजरीं, तो झट से उन्होंने करमो की इमेज को तोड़ने के लिए निर्माता गुल आनंद की फिल्म 'हीरो हीरालाल' में एक छोटी-सी, किंतु ग्लैमरस भूमिका स्वीकार कर ली और उन सारी फिल्मों के आफर ठुकरा दिये, जो उन्हें एक खास इमेज में बांध देते।

टीवी सीरियलों के नाम से ही परहेज करनेवाली दीपा साही ने सईद मिर्जा के सीरियल 'मनोरंजन' में इस आशा से काम किया था कि उनकी नयी फिल्म में वह नायिका होंगी। लेकिन मिर्जा जो फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें भी वही भूमिका है जिससे वह आतंकित हैं। दीपा का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि गोविंद निहलानी की जिन फिल्मों (पार्टी, आघात और तमस) में उन्होंने काम किया, वे फिल्में सिनेमा घरों के परदों पर चढ़ नहीं पायीं, मजबूरन छोटे परदे (टीवी) पर उसको जगह मिली।

'हीरो हीरालाल' में छोटी-सी भूमिका निभाकर दीपा बहुत खुश हैं। यह फिल्म तो सिनेमा घर में प्रदर्शित होगी ही। तब करमो की इमेज के आतंक से उन्हें छुटकारा मिल जायेगा। दीपा के इस कदम से बेचारे गोविंद निहलानी जरूर नाखुश हैं कि जिसे उन्होंने सितारा बनाने का सपना देखा था, वह खुद ही पीछे हट गयी।

श्रीप्रदा : टू-इन-वन

श्रीदेवी के सेक्स और ग्लैमर तथा जयाप्रदा की खूबसूरती का अपने को मिश्रण माननेवाली एवं दोनों के नामों को मिला कर अपना फिल्मी नाम रखने वाली श्रीप्रदा अपने को टू-इन-वन मानती हैं। श्रीदेवी की तरह सेक्स-ग्लैमर और जयाप्रदा की खूबसूरती को अपने में देखनेवाली श्रीप्रदा के पास न तो बड़े निर्माता तथा सितारे फटक रहे हैं और न ही उन्हें फटकने दे रहे हैं। वैसे श्रीप्रदा का दावा है कि उनमें सेक्स और ग्लैमर प्रदर्शन का माद्दा श्रीदेवी से भी कहीं अधिक है। खूबसूरती में वह अपने को जयाप्रदा से भारी मानती हैं। इस दावे के बाद से श्रीप्रदा अपने ग्लैमर और सेक्स की तलवार भांजते हुए फिल्मी दुनिया की अन्य ग्लैमरस अभिनेत्रियों के मुकाबले आ खड़ी हुई हैं और उस प्रकार की भूमिकाएं भी करने के लिए तैयार हैं, जैसी श्रीदेवी ने मलयालमं फिल्म 'जवानी की हवा' में शुरुआत के दिनों में की थीं। ग्लैमर की इस किलेबंदी को तोड़ने के बाद उनका इरादा है जयाप्रदाई किले पर हमला करने का। पर इन दिनों जयाप्रदा 'चेंज' के लिए अब ग्लैमरस भूमिकाएं भी करने लगी हैं। फिर ऐसे में श्रीप्रदा क्या टू-इन-वन कहला पायेंगी?

श्रीप्रदा छाया: महेश जॉली

दोस्ती का हक

जब से मिथुन चक्रवर्ती ने केनिया के एक अरबपति फिल्म निर्माता की एक फिल्म ४० लाख रुपए में साइन की है, तब से विनोद खन्ना से लेकर कुमार गौरव तक इस चमत्कार का राज जानने के लिए उनके पीछे पड़ गये हैं। राज ऐंड राज कंपनी को लेकर 'सरपरस्त' बनानेवाले बीआर चोपड़ा ने राजेश खन्ना वाली भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को और राज बब्बर का रोल मिथुन की सिफारिश पर कुमार गौरव को थमा दिया है। इस तरह बीआर चोपड़ा ने फिल्मों में बुरी तरह से पिटते रहे कुमार गौरव को अपनी फिल्म में मौका देकर राजेंद्र कुमार के उस अहसान को चुकता कर दिया, जिसे राजेंद्र कुमार ने चोपड़ा की फिल्म 'धूल का फूल' में काम करके चोपड़ा की डूबती नैया को बचाया था।

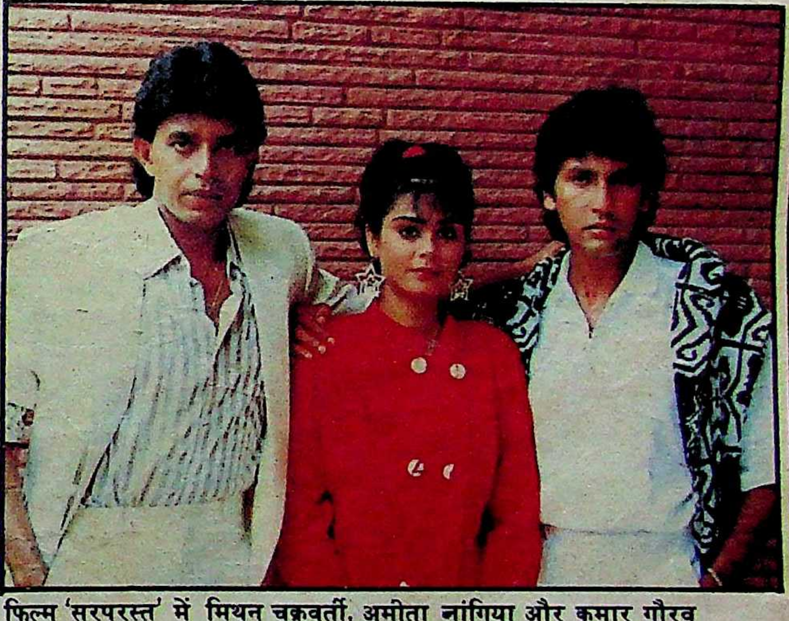

फिल्म 'सरपरस्त' में मिथुन चक्रवर्ती, अमीता नांगिया और कुमार गौरव

श्रीदेवी से दोस्ती होने के पहले मिथुन की स्थिति फिल्में चलने के बावजूद दोयम दर्जे के कलाकार की थी। श्रीदेवी का साया मिलते ही उन्हें रुतबा और प्यार दोनों मिल गये।

—अखबारी लाल

मोजाम्बीक के राष्ट्रपति

भारत से उम्मीद

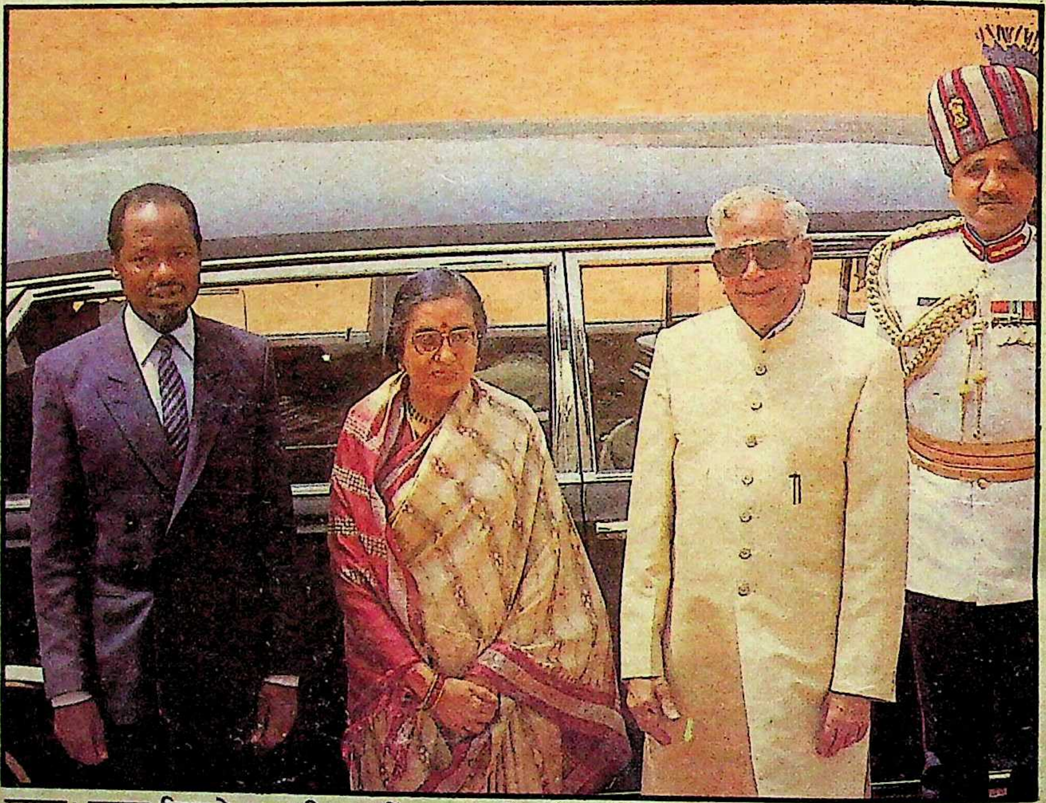

स्वागत: जनरल चिसानो, राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और श्रीमती वेंकटरमण

छाया: सीएनएस

दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बीक के राष्ट्रपति मेजर जनरल जो आक्विम अलबर्टो चिसानो १४ मई, १९८८ को तीन दिवसीय सरकारी यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी, तीन काबीना मंत्री, एक उपमंत्री सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति थे। चिसानो पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी।

राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत राष्ट्रपति वेंकटरमण, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। राष्ट्रपति चिसानो के सम्मान में दिये गये रात्रिभोज में राष्ट्रपति वेंकटरमण ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी नीति पर दुख प्रकट किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि यह जुल्म एक दिन अवश्य खतम होगा। नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका के शासन को राष्ट्रपति वेंकटरमण ने अवैध बताया।

संवाददाताओं से बात करते हुए राष्ट्रपति चिसानो ने आशा व्यक्त की कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि मोजाम्बीक की जनता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी आदि भारतीय नेताओं का बहुत सम्मान करती है। राष्ट्रपति चिसानो ने गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीकी लोगों के स्वतंत्रता-संघर्ष के लिए 'अफ्रीका कोष' की स्थापना के लिए राजीव गांधी के योगदान की सराहना की। इस समय भारत इस कोष का अध्यक्ष है।

आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मोजाम्बीक भारत का सहयोग चाहता है और भारत ने उसे इन क्षेत्रों में सहायता का आश्वासन दे दिया है। भारत ने मोजाम्बीक में द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर अफ्रीका कोष के अंतर्गत चार परियोजनाएं स्वीकार की हैं। भारत अब तक मोजाम्बीक को १७ करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। रेल व दूरसंचार की परियोजनाओं में उसने अपने विशेषज्ञ भी भेज रखे हैं।

मोजाम्बीक १९७५ में स्वतंत्र होने से पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। यहां का इतिहास अफ्रीका के अन्य देशों की तरह ही यूरोपियों द्वारा काले अफ्रीकी लोगों के शोषण और उत्पीड़न का इतिहास रहा है। यहां के प्रतिशत लोग बन्तू भाषा बोलते हैं, परंतु यहां की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली ही है।

दक्षिण अफ्रीका के इस देश की राजधा मपूतो है। देश के अधिकतरभाग में जंगल हैं और अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है। यहां के नब्बे प्रतिशत लोग खेती करते हैं और मुख्य रूप से काजू, गन्ना, चाय आदि उपजाते हैं। कोयले, हीरे और बाक्साइट का खनन होता है, परंतु खनिज संपदा का बहुत उपयोग हो रहा है। यहां के अधिकतर उद्यो कच्चे माल को तैयार करने तक ही सीमित हैं। यहां सीमेंट और खाद के भी कारखाने हैं।

—श्रीप्रकाश

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक १३ १५ जुलाई, १९८८

आवरण कथा

३७

इलाहाबाद के ऐतिहासिक उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह की विजय को विपक्ष कांग्रेस-इ के अंत की शुरुआत बता रहा है। इस उपचुनाव में एक ओर कांग्रेस की प्रांतीय और केंद्रीय शक्ति लगी हुई थी और दूसरी ओर संपूर्ण विपक्ष राजा के साथ जुटा हुआ था। जैसा भीषण चुनावी संग्राम इलाहाबाद में हुआ, वैसा आजादी के बाद कभी देखने को नहीं मिला। यह महायुद्ध कैसे लड़ा गया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जीत कैसे हासिल की?

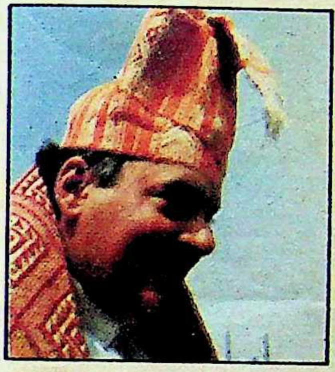

१७ विशेष रिपोर्ट

प्रधानमंत्री राजीव गांधी खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों के दौरे क्यों करते हैं?

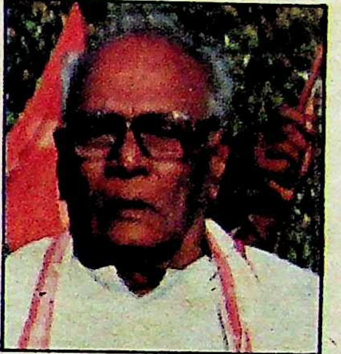

२८ राजेश्वर राव

देश की ज्वलंत समस्याओं के संदर्भ में भाकपा के वयोवृद्ध महासचिव राजेश्वर राव से 'माया' का विशेष साक्षात्कार

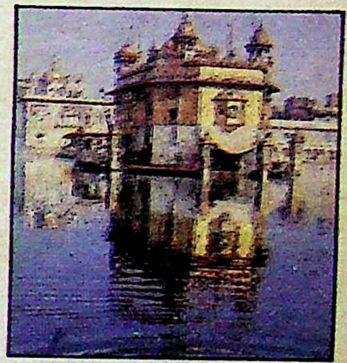

३३ पंजाब

पवित्र स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी कैसी-कैसी यातना देकर स्त्री-पुरुषों की हत्या किया करते थे?

२३ चंद्रिका केनिया

महाराष्ट्र की बहुचर्चित महिला मंत्री भी क्या अंतुले की तरह ट्रस्ट-विवाद में फंस गयी हैं?

९६ यादें

प्रसिद्ध फिल्म गीतकार हसरत जयपुरी की यादों के आइने में राजकपूर की झलक:

९० विंबलडन

विंबलडन का लान टेनिस के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान क्यों और कैसे बना?

DUPLICATE
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

चुनाव-चित्र २
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
दिल्ली दरबार/हे राम १०
फोटोफीचर १३
चर्चा/विवाद में 'राम' ६६
चर्चा/राज बब्बर ने ऐसे किया चुनाव-प्रचार ६८
बिहार/विधायक गये हरिद्वार, खाकर आये मार ६९
राजस्थान/ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट: राजस्थान सरकार के लिए सिरदर्द ८०
मध्य प्रदेश/मोतीलाल वोरा से बातचीत
मध्य प्रदेश/थानेदार अपने ही आतंक का शिकार
मध्य प्रदेश/मजदूरों में घुलकर बंट रही बीमारी ८६
कर्नाटक/रशीद हत्याकांड ८७
लोग ९५
स्त्री/राजकपूर की स्त्रियां ९८
कार्टून १००
बेढब १०१
परदे के पीछे १०२
सेहत १०४

आवरण पारदर्शी

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

• प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०-२८०, • दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१७४१३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, सेंचुरा अपार्टमेंट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७५०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६११६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं ५२ (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९१०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं—उनमें इस बार का इलाहाबाद लोकसभा का उपचुनाव हर दृष्टि से अभूतपूर्व रहा। बोफोर्स प्रकरण के कारण अमिताभ बच्चन द्वारा खाली की गयी इस सीट को पुनः हासिल करने के लिए जहां कांग्रेस-इ ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया, वहीं संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के निर्णायक चुनाव को लड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इस बार जैसा चुनाव प्रचार हुआ—वैसा इलाहाबाद में आज तक नहीं हुआ। बंदनवार, तोरणद्वार, पोस्टरों की सतरंगी लड़ाई का कोई जवाब नहीं था। प्रस्तुत हैं, चुनाव-प्रचार की कुछ झलकियां:

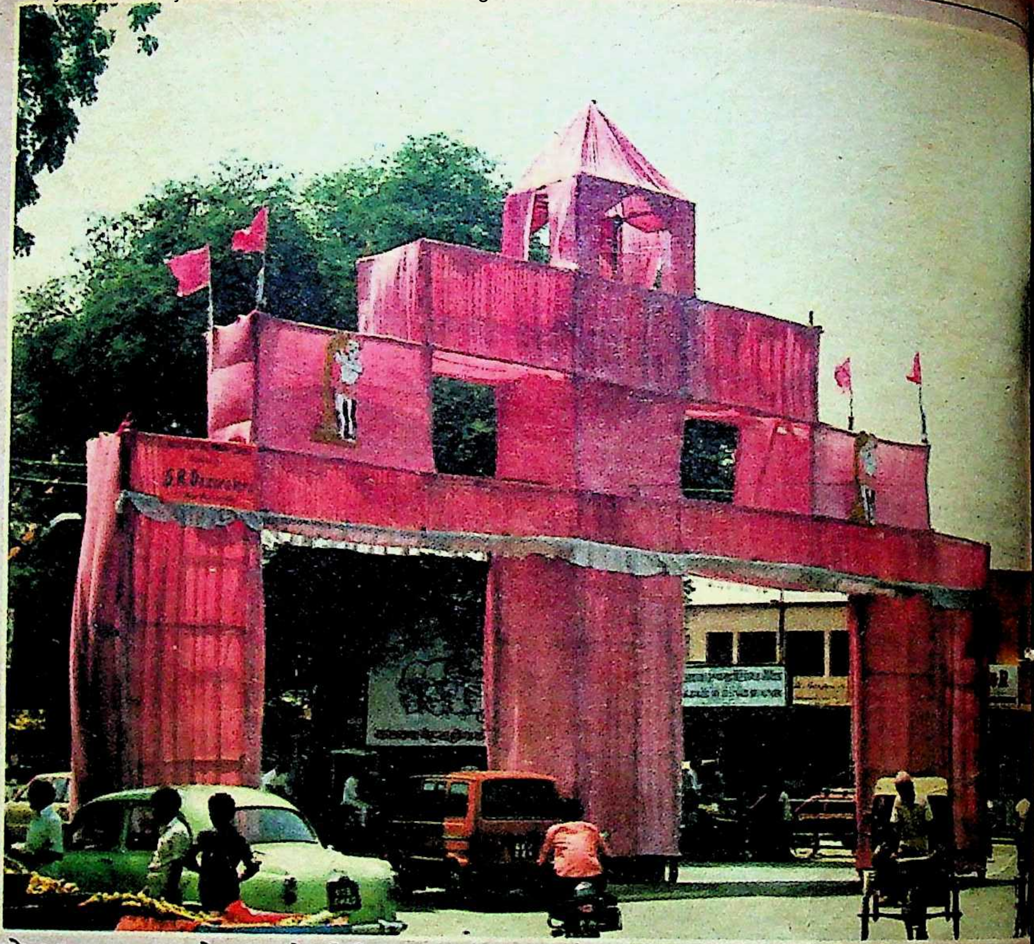

तोरणद्वार का जवाब तोरणद्वार से: सिविल लाइंस में वीपी सिंह समर्थकों द्वारा बनवाये गये दो तोरणद्वारों में से एक

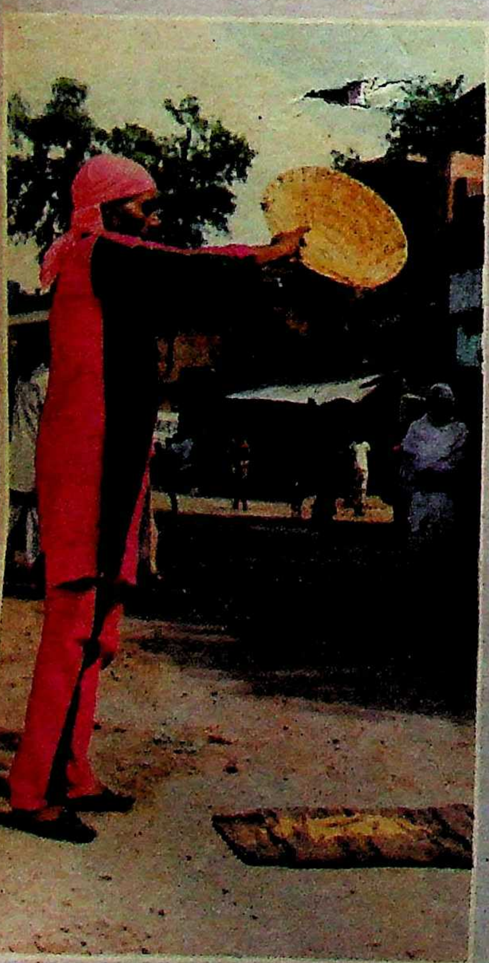

ऐसे किया गया चुनाव चिह्न का प्रचार

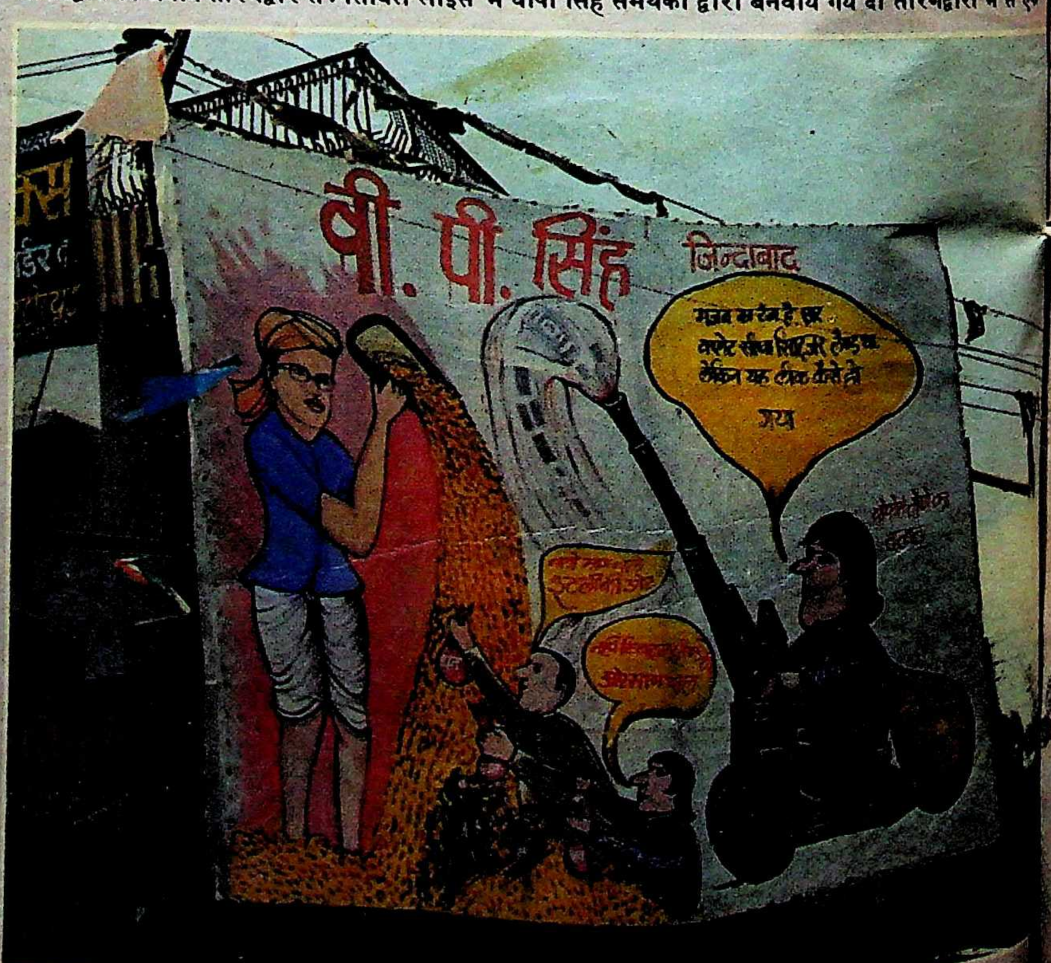

बोफोर्स पर अनाज ओसाता किसान भारी पड़ा: एक कार्टून

रों में से एक

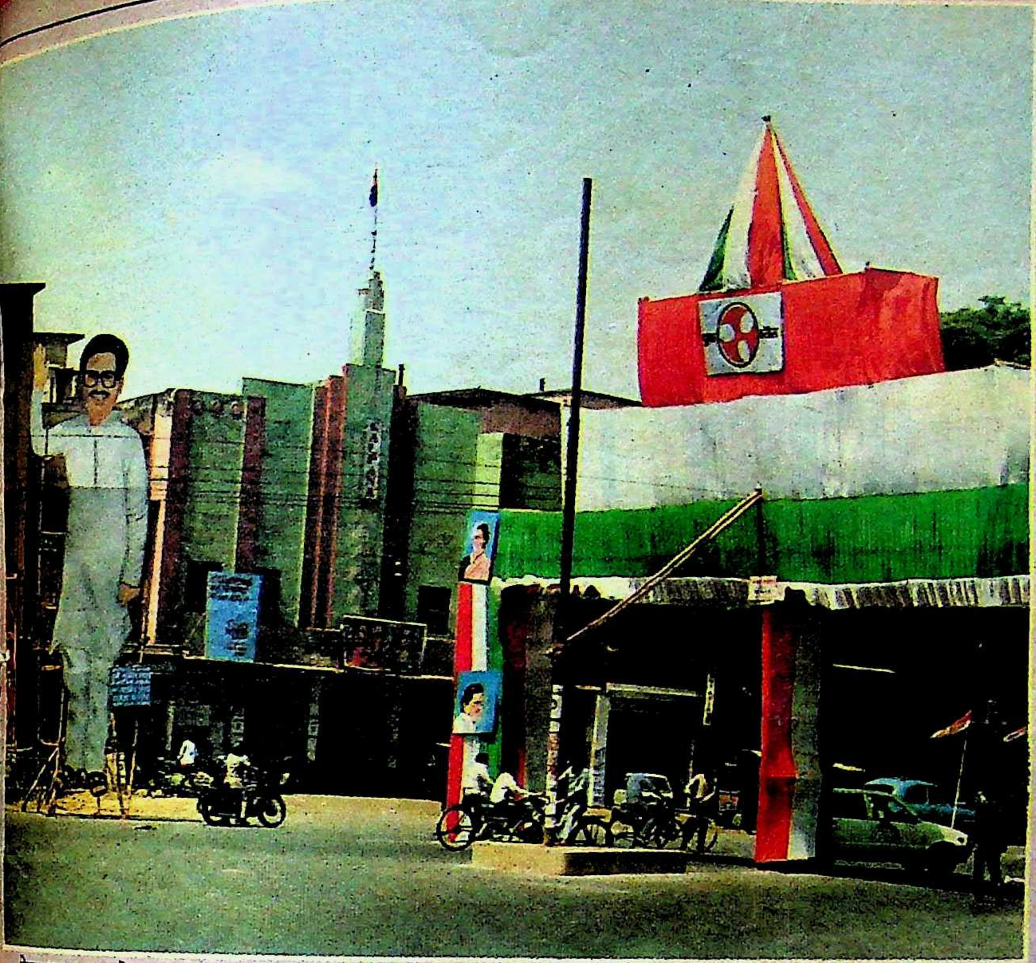

तेरह हजार का तोरणद्वार : कांग्रेस-इ द्वारा सिविल लाइंस में तोरणद्वार और सुनील शास्त्री का आदमकद चित्र

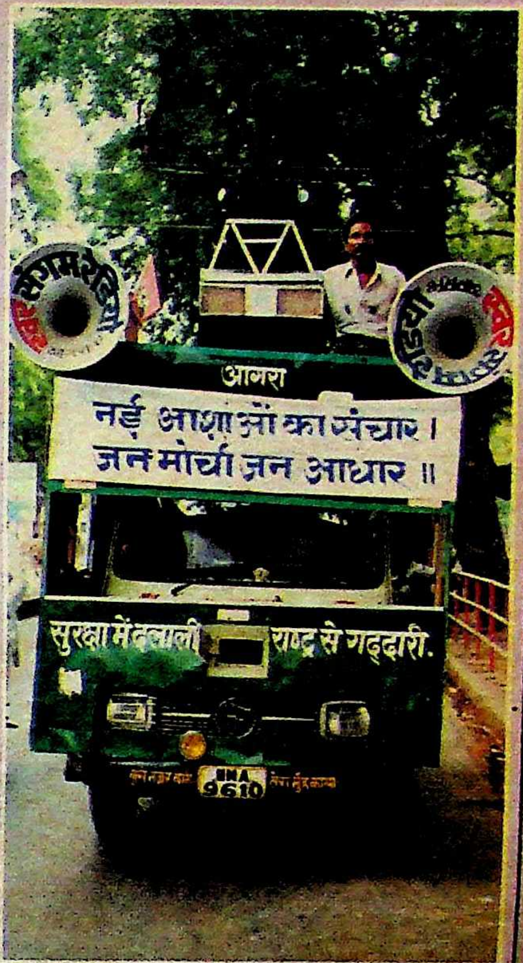
आगरा
नई आशाओं का संचार।
जन मोर्चा जन आधार ॥
सुरक्षा में दलाली राष्ट्र से गद्दारी।

जन समर्थन : राजा के लिए आगरा से पहुंचे प्रचारक

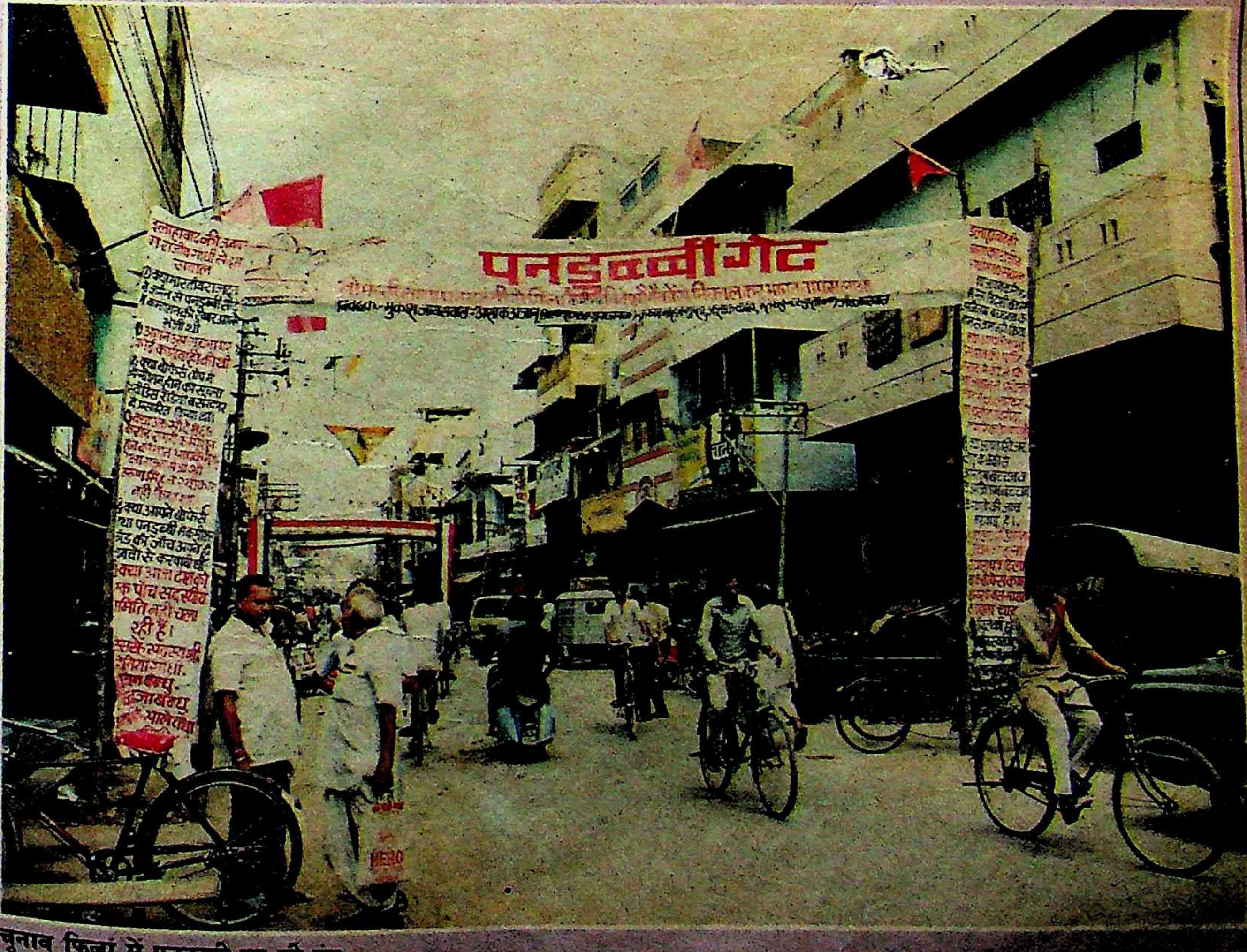

चुनाव फिज़ां में पनडुब्बी का भी रंग

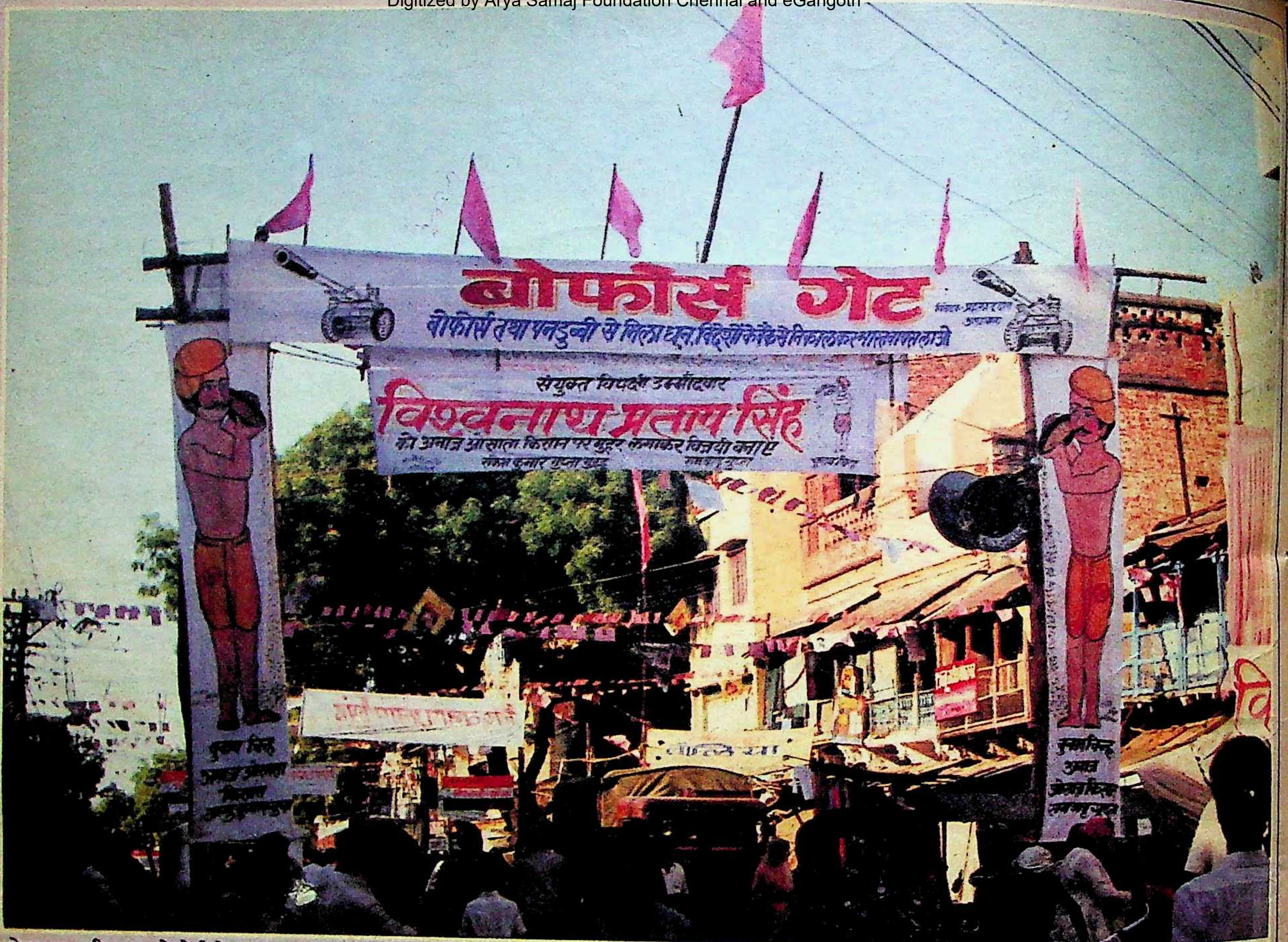
बोफोर्स गेट
बोफोर्स तथा पनडुब्बी से मिला धन विदेशों के बैंकों से निकालकर भारत वापस लाओ
संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार
विश्वनाथ प्रताप सिंह

तोरणद्वार भी बना बोफोर्स के नाम

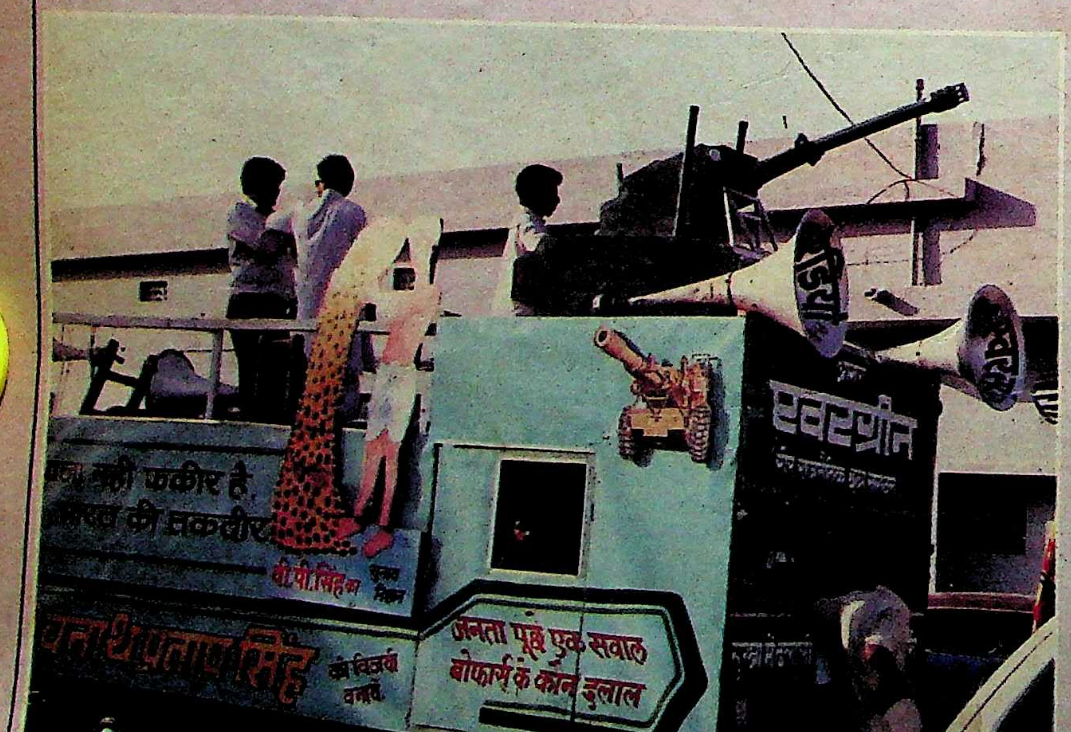
फकीर है
की तकदीर
वी.पी. सिंह का
नाथ प्रताप सिंह
को विजयी बनायें
जनता पूछे एक सवाल
बोफोर्स के कौन दलाल
एवरग्रीन

भ्रष्टाचार का प्रतीक: बोफोर्स तोप का एक चलता-फिरता माडल, जिसे शहर में घुमाया गया

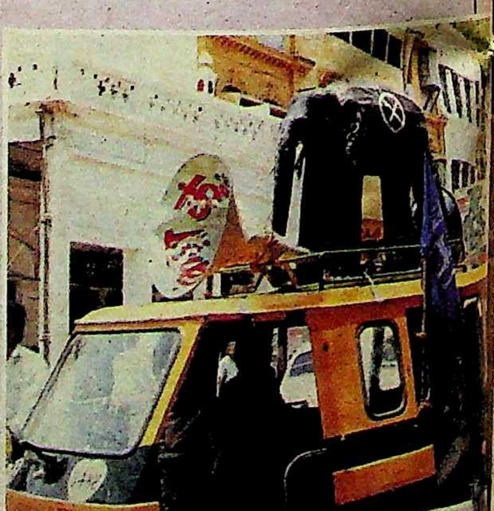

कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर : कांशीराम का चुनाव चिह्न (हाथी)

छाया : मनमोहन शर्मा, वसीमुल हक

माया
इलाहाबाद चुनाव
राजा का जोर कितना?
सुनील मैदान में क्यों?

इलाहाबाद चुनाव

माया' का ३० जून का अंक मिला। साज-सज्जा, आवरण, चित्र-वैचित्र्य देखकर तबीयत खुश हो गयी। आवरण कथा 'इलाहाबाद चुनाव' के तीनों पार्ट पढ़े। दुख है कि आपने कांशीराम को ठीक से कवर नहीं किया। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के तो आप पहले से ही समर्थक रहे हैं, इसलिए उनके झूठ और फरेब को आपने बड़ी बखूबी से नजरंदाज कर दिया है। कथा से तो आपने उन्हें जिताने में कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, लेकिन देखना है कि आपके राजा इलाहाबाद में विजय पताका फहराने के बाद देश के लिए क्या करते हैं। चाहे भले वह देश के लिए कलंक न हों, लेकिन क्या वह देश की तकदीर बन सकेंगे?. क्या महंगाई का चढ़ता पारा उतर सकेगा, क्या बेरोजगारों की बढ़ती कतार छंट सकेगी? चोरी-डकैती-बलात्कार पर क्या अंकुश लग सकेगा? उससे भी बढ़-चढ़कर उग्रवाद तथा अलगाववाद की समस्या पर वीपी सिंह और उनके चहेते क्या काबू पा सकेंगे? कांग्रेस-इ प्रत्याशी की खिंचाई आपने उचित ही की है। एअर कंडिशन में बैठकर मस्ती मारनेवाले कांग्रेसियों को अब पता चल रहा होगा कि ४६° की लपट में लोग कैसे जीवन बिताते हैं? अच्छा है, वे अभ्यास कर लें, न जाने कब कुरसी उनके नीचे से खिसक जाये। कांशीराम, जो जात-पात का सहारा लेकर चुनावी महाभारत में भिड़े हैं, उनका हारना नितांत आवश्यक है। बहरहाल कुल मिलाकर, अबकी 'माया' वाकई संग्रहणीय है।—**हरिश्चंद्र मिश्र, फूलबाग, कलकत्ता**

'माया' की भविष्यवाणी कितना रंग लाती है?

३० जून '८८ की 'माया' की आवरण कथा पढ़ी, सचमुच काबिले तारीफ है। यह तो तय है कि 'माया' वह खबर देती है, जिसकी किसी को खबर नहीं होती। लेकिन देखना है कि 'माया' ने जो इस अंक में लिखा है, वह कितना सच होता है, "अमिताभ बच्चन द्वारा किये गये आसमानी वादों के पूरा न होने से भी आम इलाहाबादी का कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। इसका लाभ राजा को मिलेगा। राजा व्यवस्था के बदलाव के जो सपने दिखा रहे हैं, उनसे भी लोग मोहित हो रहे हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की साख घटी है। कोई और चमत्कार नहीं हुआ, तो कांशीराम केवल वोट तोड़ने और हार-जीत का अंतर घटाने में भूमिका निभायेंगे। कांशीराम ज्यादातर कांग्रेस के वोट बैंक (हरिजन) में सेंध लगायेंगे, जिसका लाभ राजा को मिलेगा। ऐसी स्थिति में अब तक पलड़ा राजा का ही भारी है। लेकिन 'माया' ने राजा से जब सवाल किया कि आपको खतरा किससे है, तो उनका एक मात्र उत्तर था, 'वीर बहादुर की हाथ की सफाई से।'

—त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, पुनौरा, सीतामढ़ी, बिहार

आपरेशन ब्लैक थंडर

'माया' के १५ जून के अंक में 'आपरेशन ब्लैक थंडर' के बारे में ब्योरा पढ़ने को मिला। दरअसल जब तक सरकार संपूर्ण पंजाब में हिंसा की लहर को रोक नहीं पाती, तब तक ऐसे तमाशों को बेमानी माना जाना चाहिए। आम नागरिक को स्वर्ण मंदिर की मर्यादा की बहाली की उतनी चिंता नहीं है, जितनी अपने जान-माल की रक्षा किये जाने की। दुर्भाग्यवश, कत्लेआम अभी तक जारी है और सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए नये-नये नाटक रच रही है। उसे यह दिवास्वप्न देखना छोड़ देना चाहिए कि लोकसभा के चुनावों से कुछ माह पूर्व वह आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाकर जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जायेगी।

—लोकवास शुक्ला, नयी दिल्ली

माया' का १५ जून, १९८८ का अंक देखा। 'आतंकवादियों को समर्पण करना पड़ा' शीर्षक लेख में सामग्री बहुत कम दी गयी है। जिस तरह मैंने दूसरी पत्र-पत्रिकाओं में मशहूर आतंकवादी सुरजीत सिंह पेंटा तथा कारज सिंह थंडे का साक्षात्कार पढ़ा, वैसी ही उम्मीद मैं 'माया' से लगाये बैठा था। दूसरी तरफ चित्रों के मामले में भी इस बार 'माया' पीछे रह गयी। अगर यह सारी जानकारी 'माया' में दी जाती, तो इस विशेष रिपोर्ट को चार चांद लग जाते।

—अश्वनी कुमार, रघुवीर नगर, दिल्ली

कायल हो गया

'माया' के १५ जून के अंक में मेनका गांधी का साक्षात्कार पढ़कर उनकी दो टूक जवाब देने की शैली का मैं तो कायल हो गया। राजीव गांधी के बारे में शक की पुष्टि उनके ही घर के सदस्य ने जिस स्पष्टता से की है, उसकी मिसाल कम ही देखने में आती है। साक्षात्कार से पता चलता है कि वह एक सुलझी विचारों वाली राजनीतिज्ञ हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा हिंदुस्तान की गरीब जनता की कमाई को दोस्तों की नियुक्तियों तथा पिकनिक पर खर्च करना वास्तव में चिंतनीय है। मेनका गांधी ने ऐसे समय में अपने दल का 'जनता पार्टी' में विलय करके वास्तव में देशभक्ति का कार्य किया है।—**रविंदर सूदन, ३०६२, सेक्टर-१, वाहन निर्माणी स्टेट, जबलपुर**

खोजी लगा

'माया' के १५ जून, १९८८ के अंक में प्रकाशित लेख 'जमीनों की अवैध सौदेबाजी कौन कर रहा है?' बहुत ही सारगर्भित व खोजी लगा। इससे जाहिर होता है कि पक्ष-विपक्ष के बड़े नेता एवं अधिकारी इन जमीनों के अवैध धंधे में लिप्त हैं।

विडंबना की बात है कि जयपुर विकास प्राधिकरण भी कृषि-भूमि के अवैध धंधों का अखाड़ा बना हुआ है। साथ ही राज्य का आवासन मण्डल भी अपनी जिम्मेदारी में खरा नहीं उतर रहा है? इन दोनों संस्थाओं की निष्क्रियता के कारण ही गृह निर्माण समितियों के अवैध धंधे पनप रहे हैं। साथ ही उन लोगों की गृह निर्माण सहकारी समिति पर रोक लगायी जानी चाहिए, जिनकी हैसियत पहले क्या थी और अब क्या है?—**ओम तंवर, 'आनंदपुरी', जयपुर, राजस्थान**

अरुण सिंह ने मुंह खोला

१५ जून के अंक में प्रकाशित राजनीतिक समीक्षक रजिंदरपुरी का सटीक विश्लेषण 'अरुण सिंह ने मुंह खोला' पढ़ा। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गयी व्यापक मुहीम क्या सिर्फ कुछ निःसहाय लोगों के खिलाफ ही है? दूसरी ओर बोफोर्स घोटाले को जिस प्रकार पुनः उजागर किया जा रहा है, वह वास्तव में मात्र एक राजनीतिक चाल है, इसका कोई औचित्य नहीं।

—मिलिंद के मुंगी, १७—अशोक भवन, स्टेशन रोड, रतलाम, मप्र

एक व्यक्तित्व ऐसा भी

१५ जून '८८ की 'माया' में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डा० रामदयाल मुंडा के व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से परिचित होने का मौका मिला। समुचित मेहनत और भाग्य ने उनका साथ दिया है। वह गुदड़ी के लाल हैं। पर बड़े दुख की बात है कि उनके अथक प्रयास के बावजूद विश्वविद्यालय पतन की ओर जा रहा है। न परीक्षाएं समय पर होती हैं और न शिक्षकों को वेतन ही समय पर मिलता है। सारा विश्वविद्यालय परिसर ही दूषित हो गया है। देखना है कि डा० मुंडा अपने 'मिशन' में कहां तक सफल हो पाते हैं।

—दिव्यम, हजारीबाग, बिहार

संवैधानिक अधिकारों का हनन

१५ जून, १९८८ की 'माया' पढ़ी। आपका लेख 'सेवेंथ डे ऐडवेंटिस्ट—संवैधानिक अधिकारों का हनन' बड़ा न्यायसंगत लगा। वैसे विदेशी मिशनरी इस देश में सेवा कार्य करने और प्रभु ईशु के अनुसार अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का संदेश देने आये थे, लेकिन भारतीय ईसाइयों ने उनका अनुसरण न करके अपनी स्वार्थ-सिद्धि करनी शुरू कर दी। सेवेंथ डे ऐडवेंटिस्ट के अधिकारी अपने बच्चों को या तो विदेशों में शिक्षा के लिए भेजते हैं, या उन्हें सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालयों

चिट्ठियां

में भेजते हैं और इनका अनुसरण यदि कोई कर्मचारी करे, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेवेंथ डे ऐडवेंटिस्ट स्कूल, जिसकी शाखाएं पूरे भारत में हैं, यदि उनकी छानबीन की जाये, तो पता लगता है कि जो पैसा स्कूल से मिलता है, इसके अधिकारी उसका उपयोग अपनी हविशपरस्ती और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने में लगाते हैं।—**एचआर मैसी, जालंधर, पंजाब**

'माया' का जून प्रथम अंक पढ़ा, जिसमें आपने 'सेवेंथ डे ऐडवेंटिस्ट' मिशन के भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है, लेकिन इस संबंध में मुझे यह कहना है कि यह भ्रष्टाचार केवल इसी मिशन में नहीं है, बल्कि अन्य मिशनों में इससे भी अधिक है। चर्च आफ़ नार्थ इंडिया की लखनऊ डायसेस ने मुझे और मेरी पत्नी को मिशन स्कूल मिरजापुर से बिना किसी कारण ५ वर्ष की नौकरी के बाद निकाल बाहर किया था। यह हमारे अधिकारों का शोषण व उत्पीड़न नहीं, तो और क्या है?—**एपी सिंह, सेंट जान्स स्कूल, मिरजापुर**

कुछ आप बीती, कुछ पर बीती

प्रिय सखी! 'माया' तुम माह में दो बार जब भी हमारे द्वारे दस्तक देती हो, तो सर्वप्रथम मैं ही तुम्हें पढ़ती-गुनती हूं। तुम्हारे १५ जून के अंक में जो बात आत्मा को व्यथित कर गयी—वह है, तुम्हें सजाने-संवारने में योगदान देने वाले पत्रकार भाइयों के प्रति दुर्व्यहार व उत्पीड़न की गाथा। वह भी मुख्यमंत्री के अनुज ठाकुर गुलाब सिंह व उनके गुर्गों द्वारा, जिनके चर्चे गोरखपुर ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश में हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नित्य गला फाड़कर यह कहते नहीं थकते कि प्रेस की स्वतंत्रता सदा देशहित में रही है। लेकिन उन्ही के एक मुख्यमंत्री के भाई क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं दीख रहा है।—**अनु सिंह, इलाहाबादी**

१५ जून, १९८८ की 'माया' के अतर्गत 'कुछ आप बीती, कुछ पर बीती' शीर्षक में पत्रकार उत्पीड़न पढ़ा। पूरा पृष्ठ पढ़ने के बाद एक पुरानी कहावत याद आ गयी कि जब मेड़ ही खेत को खाने लगे, तो खेत को कौन बचाये? यह कहावत उत्तर प्रदेश प्रशासन पर अक्षरशः सत्य उतरती है। धिक्कार है ऐसी सरकार को जो एक निष्पक्ष समाचार पत्रिका के संवाददाताओं के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करती है।

खैर, हमें फख्र है 'माया' पर, इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। 'माया' को निष्पक्ष लेखन के लिए आज मैं फिर दिली मुबारकवाद देता हूं। —**ब्रजपाल सिंह जड़ौदा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**

कांग्रेस की हार ही होगी!

इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव देश तथा विदेश के लिए भी सर्वाधिक चर्चित बना हुआ है। कांग्रेस ने सुनील शास्त्री को संसदीय चुनाव का उम्मीदवार इसलिए बनाया, क्योंकि सुनील शास्त्री के पीछे लालबहादुर शास्त्री का विराट व्यक्तित्व था। अगर सुनील शास्त्री चुनाव जीत भी जाते हैं, तो यह कांग्रेस की हार ही होगी। निश्चय ही अमिताभ बच्चन को खड़ा करवाना था, ताकि हिंदुस्तान की समस्त जनता देखती और समझ पाती। अमिताभ को नहीं खड़ा कर सुनील शास्त्री को गुप्त ढंग से अचानक उम्मीदवार घोषित करना राजीव गांधी तथा कांग्रेस की हार है।

—**अरुण कुमार मंडल, मोफट गंज, गरेड़ी टोला, वार्ड नं० २८, कटिहार**

प्रतिवाद

आपके ३१ मई, १९८८ के अंक में 'तिकड़मों का केंद्र' शीर्षक से रतींद्रनाथ और नवलेश पाठक की एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें मेरा नाम लेकर मुझसे संबद्ध ऐसी बातें लिखी गयी हैं, जिनसे मेरा न तो कोई संबंध है और न इन दोनों लेखकों ने यह रिपोर्ट लिखे जाने से पहले मुझसे कोई संपर्क किया। आप इन दोनों लेखकों से संपर्क करके तथ्यों का सही परीक्षण करवाकर मुझे तुरंत सूचित करें, अन्यथा मुझे अवांछित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।—**देववीर सिंह, सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पदाधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय समिति, पटना।**

खयालात

अगर आप इस तूफान को रोक नहीं सकते, तो हम खतरे में पड़ सकते हैं।— **उप्र के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह इलाहाबाद में अपने कार्यकर्ताओं से**

सत्ता का सुख भोग चुके कुछ लोगों ने राजीव गांधी की पीठ में छुरा भोंक दिया।—**सुनील शास्त्री**

विपक्षी दल बरसाती नाले हैं। —**अभिनेता अरुण गोविल इलाहाबाद में**

वह अभिनय तो राम का करता है, पर काम रावण के लिए करता है। —**वीपी सिंह अभिनेता अरुण गोविल के बारे में**

यह तो ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि इसने राम से भी आत्मसमर्पण करवा लिया।—**इलाहाबाद में देवीलाल, अरुण गोविल के आने पर**

अगर पंजाब मुझे सौंप दिया जाये, तो मैं दस दिनों में सारी खुराफात खतम कर दूंगा।—**बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशी राम**

वीपी सिंह अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में राजपूत कांग्रेसी के अलावा कुछ नहीं थे।—**एम जे अकबर, संपादक टेलीग्राफ**

सुनील शास्त्री

वीपी सिंह सत्ता के सौदागर हो गये हैं।—**इंका के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम केसरी**

अगर कांग्रेस ने गडबड की, तो हम इलाहाबाद को पानीपत का कुरुक्षेत्र बना देंगे।—**अकबर अहमद डंपी, इलाहाबाद की एक जनसभा में**

वी०पी० सिंह

किसी फिल्म या टीवी सीरियल में भगवान राम की भूमिका करने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो जाता।— **कमलापति त्रिपाठी**

देवी लाल झूठ का बैंक है।—**भजन लाल पाली (राज०) चुनाव प्रचार के दौरान**

मैं यह दावा नहीं करता कि मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार हूं। —**गोपी कृष्ण अरोड़ा, 'हिंदुस्तान टाइम्स' में**

मुझे राजनीतिक रूप से खतम करने का प्रयास न केवल हेगड़े, बल्कि जनता पार्टी को भी मिट्टी में मिला देगा। —**कर्नाटक के असंतुष्ट नेता एचसी देवगौड़ा**

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसे तत्वों के हाथों में खेल रही है, जिन्हें न तो सिखों और न ही देश के हितों की चिंता है।—**सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत**

मैं कभी खबरों में रहने के लिए हथकंडे नहीं अपनाता।—**इयान बाथम 'स्पोर्ट्स वीक' में**

मैं रोल के मामले में अपनी मां से भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी।—**श्रीदेवी, 'आनंद' में**

रैपिडैक्स® इंगलिश स्पीकिंग कोर्स

एक रिकार्ड

3,00,00,000 तीन करोड़ से अधिक पाठकों द्वारा अपनायी गयी भारत की बारह भाषाओं में प्रकाशित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक

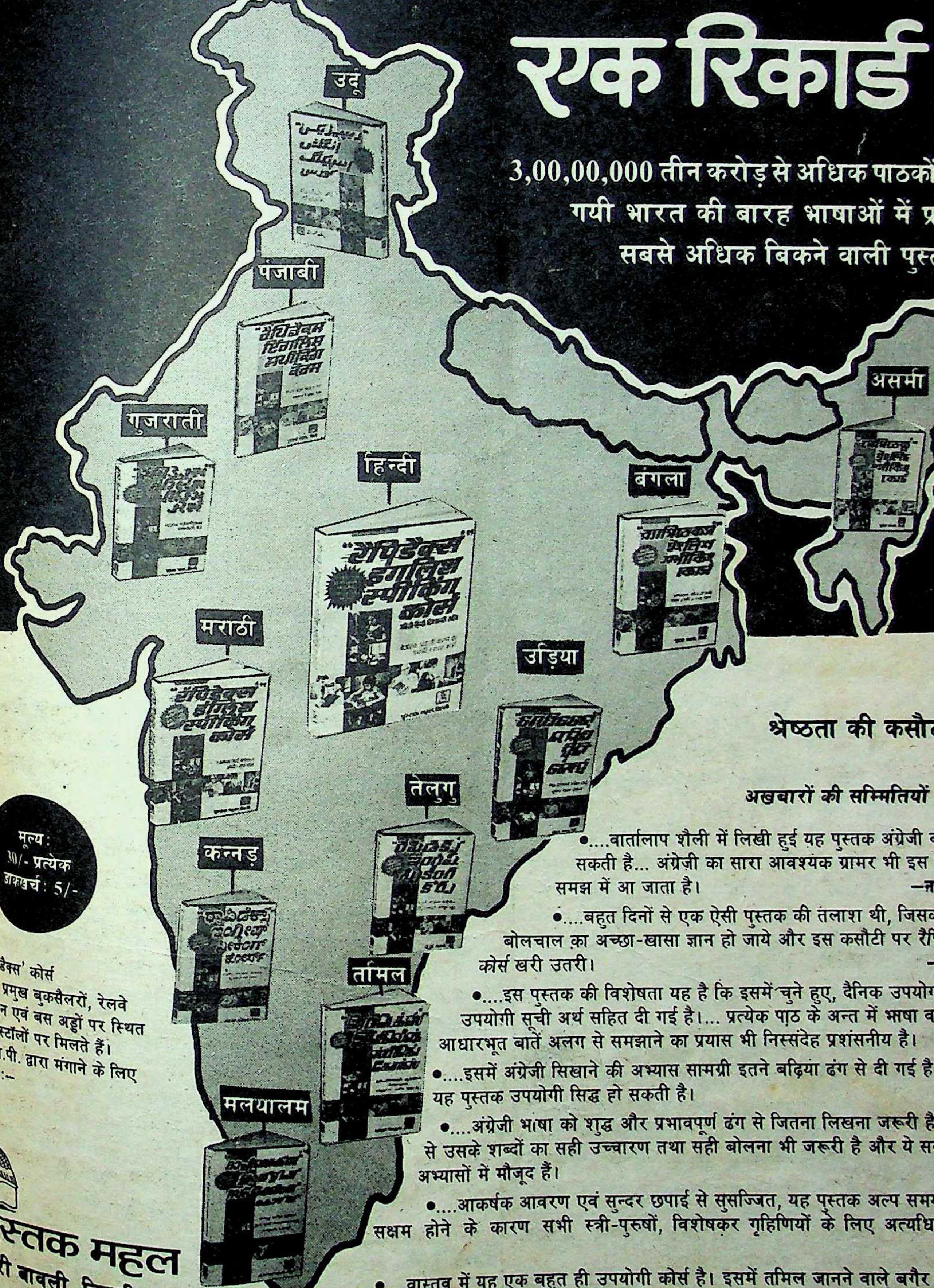

सभी कोर्सों में बड़े साइज़ के 400 से अधिक पृष्ठ

मूल्य :
30/- प्रत्येक
डाकखर्च : 5/-

श्रेष्ठता की कसौटी

देशभर के प्रसिद्ध अखबारों की सम्मितियों में से कुछ के अंश :–

●....वार्तालाप शैली में लिखी हुई यह पुस्तक अंग्रेजी बोलना आसानी से सिखा सकती है... अंग्रेज़ी का सारा आवश्यक ग्रामर भी इस पुस्तक को पढ़कर स्वतः समझ में आ जाता है। **–नवभारत टाइम्स, दिल्ली**

●....बहुत दिनों से एक ऐसी पुस्तक की तलाश थी, जिसको पढ़ते-पढ़ते ही अंग्रेजी बोलचाल का अच्छा-खासा ज्ञान हो जाये और इस कसौटी पर रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स खरी उतरी। **–बम्बई समाचार, बम्बई**

●....इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें चुने हुए, दैनिक उपयोग में आने वाले शब्दों की उपयोगी सूची अर्थ सहित दी गई है।... प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याकरण सम्बन्धी कुछ आधारभूत बातें अलग से समझाने का प्रयास भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। **–जुगान्तर, कलकत्ता**

●....इसमें अंग्रेजी सिखाने की अभ्यास सामग्री इतने बढ़िया ढंग से दी गई है कि कान्वेंट स्कूलों में भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। **–दिनामानी, मद्रास**

●....अंग्रेजी भाषा को शुद्ध और प्रभावपूर्ण ढंग से जितना लिखना जरूरी है, उतने ही प्रभावपूर्ण ढंग से उसके शब्दों का सही उच्चारण तथा सही बोलना भी जरूरी है और ये सब गुण पुस्तक के क्रमवार अभ्यासों में मौजूद हैं। **–गुजरात मित्र, सूरत**

●....आकर्षक आवरण एवं सुन्दर छपाई से सुसज्जित, यह पुस्तक अल्प समय में ही अंग्रेजी सिखाने में सक्षम होने के कारण सभी स्त्री-पुरुषों, विशेषकर गृहिणियों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। **–डेक्कन क्रोनिकल**

●....वास्तव में यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इसमें तमिल जानने वाले बगैर किसी परेशानी के ग्रेजुएट जैसी अंग्रेजी बोल सकते हैं। **–सण्डे स्टैण्डर्ड, मद्रास**

●....रैपिडैक्स कोर्स ही एकमात्र ऐसा विस्तृत कोर्स है, जो हर किसी को 60 दिन में अंग्रेजी बोलना व लिखना बिना किसी शिक्षक या स्कूल में गये, सिखाने में सक्षम है। **–नागपुर टाइम्स, नागपुर**

●....अंग्रेजी सीखने के लिए इसका क्रमवार अभ्यास अपनी एक विशेषता है। **–गुजरात समाचार, अहमदाबाद**

'रैपिडैक्स' कोर्स सभी प्रमुख बुकसैलरों, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर स्थित बुक स्टॉलों पर मिलते हैं। वी.पी.पी. द्वारा मंगाने के लिए लिखें :–

पुस्तक महल
खारी बावली, दिल्ली-110006.
10-B, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
22/2, मिशन रोड, बंगलौर-560027

VAN/PM/27

मंत्रियों पर भरोसा नहीं

प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनके सचिवालय द्वारा सरकारी और प्रशासनिक प्रबंध के लिए सामान्य निर्देश जारी किये जाते हैं। किंतु इस बार जब राजीव गांधी एयर इंडिया के जंबो विमान से नौ दिन के अपने विदेश-दौरे पर गये, तो कैबिनेट मीटिंग संबंधी उनके अजूबे निर्देशों से वे राजनीतिक पर्यवेक्षक भी हतप्रभ हो गये जो राजीव गांधी की परंपरा तोड़ने की आदत के अभ्यस्त हैं।

इस बात की साफ और कड़ी हिदायत दी गयी थी कि प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। यह श्रीमती गांधी के समय की प्रथा के ठीक विपरीत था, जब सामान्यत: प्रणब मुखर्जी और यदाकदा पीवी नरसिम्हाराव जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता किया करते थे।

जब श्रीमती गांधी अमरीका में थीं और इंडियन एयरलाइंस के बोइंग विमान का अपहरण किया गया था, तो प्रणब मुखर्जी ने नरसिम्हाराव और अन्य मंत्रियों के साथ मिनी कैबिनेट मीटिंग इसलिए की थी कि यदि पाकिस्तान ने विमान को लाहौर के गद्दाफी हवाई अड्डे पर न उतरने दिया, तो क्या जवाबी कार्रवाई की जाये। तब श्रीमती गांधी को इस मीटिंग की जानकारी तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार वीएस त्रिपाठी द्वारा ही दी गयी थी।

इस समय भी पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक परिवर्तन के दौर में है, जिससे भारत में एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है। फिर भी कैबिनेट मीटिंग की मनाही है। बताया जाता है कि मंत्रियों को कोई अहम मुद्दा उभरने पर कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख, सुरक्षा सचिव टीएन शेषान और गृहराज्यमंत्री चिदंबरम से मशविरा करने को कहा गया है।

लगता है, प्रधानमंत्री की नजर में मंत्री अधिक भरोसे के नहीं रह गये हैं। एक सूत्र के अनुसार मामला वफादारी का नहीं, बल्कि उनकी काबिलीयत का है। शायद ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री सचिवालय के कंप्यूटर में दर्ज अपनी काबिलीयत का लेखा-जोखा मालूम हो।

भविष्य की चिंता

जब राजीव गांधी १२ जून, १९८८ को सुबह विमान से दिल्ली पहुंचे, तो उनके गुप्तचर तंत्र ने उपचुनाव संबंधी जानकारियों की मोटी फाइल उन्हें सौंप दी। उन्हें अनेक राष्ट्रीय व राज्यों के पार्टी नेताओं के आचरणों व गतिविधियों की भी जानकारी दी गयी।

यही कारण है कि कांग्रेस के नेता चाहते थे कि वे लोग अपने-अपने क्षेत्र में दौरा १२ जून के पहले कर लें, जिससे कि उनका रिकार्ड राजीव गांधी के सामने मंत्रिमंडल के हेरफेर के पहले अच्छा बन जाये।

गांधी के सलाहकारों ने यह हवा फैला रखी थी कि जो मंत्री और असंतुष्ट नेता चुनाव में मदद करेंगे, उनको उचित पुरस्कार दिया जायेगा। मगर इसका असर गुजरात में उलटा पड़ा। मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के सलाहकारों को यह फिक्र हुई कि अगर चुनाव के कारण माधव सिंह सोलंकी आगे बढ़ गये, तो उन्हें कहीं केन्द्रीय मंत्रिमंडल में न ले लिया जाये। इसी कारण वहां राम (अरुण गोविल) लाये गये और जीत का श्रेय राम को देने का प्रबंध किया गया। चौधरी की कोई होड़ ईश्वर के साथ नहीं है।

इलाहाबाद की उड़ान

इलाहाबाद के लिए इंडियन एयरलाइंस की दैनिक बोइंग उड़ान शुरू करने का विचार चंद बड़े कांग्रेसी नेताओं का था। उनका ख्याल था कि इस प्रकार दिल्ली से ६५ मिनट में वहां पहुंचने की जो सहूलियत होगी, उससे चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि विपक्ष भी इससे लाभान्वित हो रहा है, तो सब ने अब इस बात से इनकार करना शुरू कर दिया है कि इसको आरंभ कराने में उनका कोई हाथ है। खबर है कि प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकारों को एक दैनिक में छपे उस कार्टून की जानकारी दी गयी है, जिसमें दिखाया गया है कि इस उड़ान से विपक्ष को कितनी अधिक सहायता मिली है, क्योंकि कांग्रेसी नेता जहां सरकारी विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं दैनिक उड़ान न होने से विपक्षी नेताओं को ट्रेन का सहारा लेना पड़ता, किंतु अब चुनाव संपन्न होने के बाद यदि दैनिक उड़ानें रद्द की जाती हैं, तो पार्टी की साख पर भारी धक्का लगेगा।

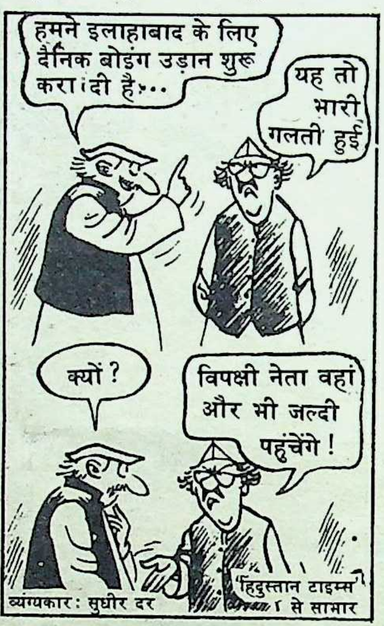
हमने इलाहाबाद के लिए दैनिक बोइंग उड़ान शुरू करा दी है...
यह तो भारी गलती हुई
क्यों?
विपक्षी नेता वहां और भी जल्दी पहुंचेंगे!

व्यंग्यकार: सुधीर दर

'हिंदुस्तान टाइम्स' से साभार

बच्चन को संदेश

प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे की टोली में शामिल उनके सूचना प्रमुख ने पश्चिम जर्मनी की राजधानी बान से बार-बार यह संदेश अमिताभ बच्चन को भेजा था कि वह इलाहाबाद जाकर चुनाव प्रचार करें। यह फैसला यह पता लगने पर लिया गया था कि अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों का संघ सुनील शास्त्री को समर्थन देने में आनाकानी कर रहा है और महिला मतदाता अमिताभ के करिश्मे से प्रभावित होंगी।

जब अमिताभ एक हफ्ते पहले दिल्ली आये, तो अगले दिन उनके इलाहाबाद जाने के पक्षधरों और विरोधियों में ठन गयी। असलियत यह है कि वह दिल्ली अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और अपने श्वसुर तरुण भादुड़ी की देखरेख करने आये थे। दोनों बुजुर्ग आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भरती हैं।

अमिताभ के कुछ करीबी साथी-सलाहकार उनके चुनाव दलदल में फंसने के कट्टर विरोधी थे। उनकी राय है कि अमिताभ अगले चुनाव के लिए खुद की जमीन तैयार करें। उनका यह भी मानना है कि तब जरूरत पड़े, तो निर्दलीय के रूप में भी खड़ा होने में उन्हें परहेज नहीं करना चाहिए।

त्रिपाठी का सहसा दौरा

बहुत कम लोगं कमलापति त्रिपाठी की बुद्धि और सूझ-बूझ का मुकाबला कर सकते हैं। त्रिपाठी रणनीति के मामले में बहुत आगे हैं। कहा जाता है कि वह चुनावों में कोई रुचि दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय किया था कि अपनी करवट वह चुनाव के नतीजों के हिसाब से बदलेंगे। मगर जब यह खबर आयी कि वीरबहादुर सिंह का तख्ता हिल रहा है, तो त्रिपाठीजी एक विशेष हवाई जहाज से इलाहाबाद जाने के लिए व्याकुल हो गये। वह भी १२ जून को जिस दिन राजीव गांधी वापस दिल्ली लौट रहे थे।

त्रिपाठी-परिवार को पूरी आशा है कि इस परिश्रम के लिए लोकपति त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंप दी जायेगी। वैसे चुनाव में लोकपति को कोई अहमियत नहीं दी गयी। ■

देख-भाल करने वाली की देख-भाल भी तो ज़रूरी है!

सुबह नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर दोपहर का भोजन, बाज़ार से चीज़ें खरीदना, घर-गृहस्थी की देखभाल.... दिन-भर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती।

मेरे डाक्टर ने हॉर्लिक्स पीने की सलाह दी, क्योंकि यह पौष्टिक है। हॉर्लिक्स से मुझे दिन-भर काम करने की शक्ति मिलती है — और थकान का नाम नहीं। इसीलिए दिन ढलने पर भी मैं परिवार के संग हंसी-खुशी के कुछ पल गुज़ार सकती हूँ।

गृहिणी के लिए शक्तिदायक पेय

हॉर्लिक्स में प्रोटीन विटामिन, खनिज पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट जैसे अत्यंत आवश्यक प्राकृतिक पोषक-तत्त्व प्रचुर मात्रा में होते हैं. जिनसे बिना थके काम करने की शक्ति मिलती है।

तभी तो दुनिया-भर में डाक्टर हॉर्लिक्स पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सारे परिवार के लिए पौष्टिकता का एक प्रमाणित साधन है।

Horlicks
The Great Nourisher
PROTEINS
VITAMINS
MINERALS
CARBOHYDRATES
ENERGY SOURCE
EASY TO DIGEST
COMPLETELY NATURAL

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 5817 HIN

हे राम !

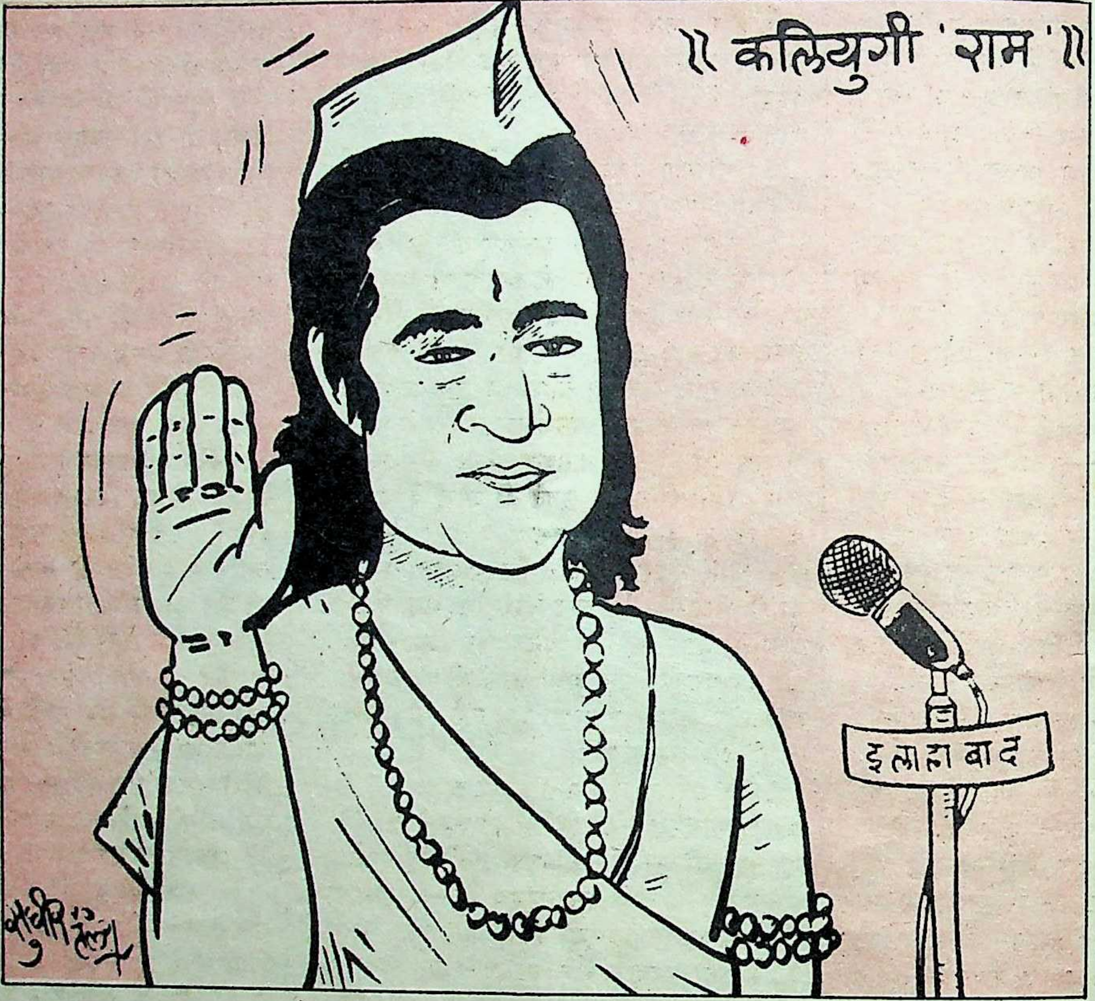

दिल्ली दरबार जब हवा (विदेश यात्रा) से जमीन (पालम हवाई अड्डे) पर उतरे, तो दरबारियों के चेहरों पर मातम छाया हुआ था। बगल में साथ उतर रहे नटवर (नटवर सिंह) से दिल्ली दरबार ने घबड़ाकर पूछा, "क्या मेरे पीछे कोई राज पुरुष जाता रहा? दरबारियों के चेहरों पर मातमी मेकअप क्यों है?" नटवर अपनी फटी हुई आवाज में कोई कूटनीतिक बात बोलें कि उसके पहले एक खबरची ने लपक कर बावर्ची स्टाइल में दिल्ली दरबार के चेहरे पर एक सवाल दे मारा, "सर, क्या आप इलाहाबाद में चुनाव हार रहे हैं?" दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये, "तेरे भेजे में यह सवाल घुसा कैसे? अरे हमने इलाहाबाद का चुनाव जीत लिया है। मुझे फोन करके गुलाम नबी ने...।" दिल्ली दरबार अपना वाक्य पूरा करें कि पहले ही खबरची को पीछे से सीताराम केसरी ने खींच लिया, "अभी थके-हारे दिल्ली दरबार जमीन पर उतरे हैं। तुम लोगों में कुछ शर्म-हया है कि नहीं। चलो, अभी फूटो शाम को २४, अकबर रोड पर मिलना, रसगुल्ले खिलायेंगे।" खबरची ने मचलने की कोशिश की, तो सुरक्षा की काली बिल्ली ने उसे 'मिऊं' करके दबोच लिया।

दरबारियों के मातमी चेहरों का रहस्य जब उजागर नहीं हुआ, तो दिल्ली दरबार ने डपट कर गुलाम नबी आजाद से पूछा, "हमने तो बहुत सा 'मुस्कानी मेकअप' इंपोर्ट करवाया था। क्या वह चुक गया? तुम लोगों के चेहरों पर मुस्कान वाला मेकअप क्यों नहीं?" गुलाम नबी खींसे निपोर कर कुछ कहें कि उसके पहले ही केसरीजी ने स्थिति को संभाल लिया—"सर, हम लोगों के चेहरों पर आपका मुस्कानी मेकअप है। लेकिन अभी-अभी हम लोग इलाहाबाद से लौटे हैं। वहां राजा मांडा का मातमी मेकअप उड़कर हमारे चेहरों पर चिपक गया। इस डर से चेहरे नहीं धोये कि कहीं मुस्कानी मेकअप भी न बह जाये। हुजूर, हम लोगों को मालूम है कि बिना मेकअप के चेहरा आपको पसंद नहीं आता। आप दरबार चलें, हम लोग मुंह धोकर फिर से मुस्कानी मेकअप कर आते हैं।" दिल्ली दरबार आश्वस्त होकर बैंड-बाजे के साथ दरबार की तरफ कूच कर गये।

दिल्ली दरबार के दरबार में पहुंचते ही सैम पित्रोदा ने मरे मन से एक दर्जन वीडियो कैसेट उन्हें थमाते हुए कहा, "सर, आपके लंगूरों (दरबारियों) ने राजा मांडा से निपटने के चक्कर में सारे इलाहाबाद की ऐसी-तैसी कर दी है। क्या-क्या कलाबाजियां पिछले १० दिनों में इन लोगों ने खायी हैं, इसी का नंगा नाच इन कैसेटों में है। पहले आप इनको देख लें, उसके बाद दरबार में अवतरित हों ताकि...।" सैम पित्रोदा अपना वाक्य पूरा करते हुए वीडियो में कैसेट फिट करने लगे। सैम कैसेट फिट करें कि उसके पहले दिल्ली दरबार गरज पड़े, "सैम, मुझे तुम्हारी इस समय यह 'तकनीकी एप्रोच' बिलकुल पसंद नहीं। मैं पहले अपने चेहरे पर—मुस्कान का मेकअप मलकर दरबारियों से मिलूंगा। उसके बाद तुम्हारे ये बासी कैसेट देखूंगा।" सैम पित्रोदा झटका खाकर रुक गये और दबी जुबान में बुदबुदाये, "सर, अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कान का मेकअप न मलें, तो

अच्छा रहेगा। वह राजा मांडा अब यह कहने लगा है कि पता नहीं दिल्ली दरबार हमेशा क्यों मुस्कराते रहते हैं।" दिल्ली दरबार फिर बिगड़ पड़े, "सैम, अब वह राजा मांडा मुझे मुस्कान का मेकअप मलने से रोकेगा। अरे जब रोम जल रहा था, तो सम्राट नीरो वायलिन बजा रहा था। क्या मैं मुस्करा भी नहीं सकता हूं।" दिल्ली दरबार के सशक्त तर्क ने सैम पित्रोदा को अपनी गरदन शुतरमुर्ग की तरह छुपा लेने के लिए पूरी तरह बाध्य कर दिया। इतने में ही जार्ज दिल्ली दरबार के पास आकर ठिठक गये। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी बोलती बंद थी। दिल्ली दरबार को बुरा लगा, जार्ज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह पूरे दरबार का माहौल मेरे हवा में उड़ते ही क्यों बदल गया! जब मैं जमीन पर आ गया हूं, तो तुम लोग जमीन पर क्यों नहीं आ रहे हो। मुझसे क्या छिपाया जा रहा है!" जार्ज हीला-हवाली करने लगे, तो दिल्ली दरबार कसकर गुर्राये, "मुझे राजा मांडा की हार के जश्न की तैयारी पर दरबारियों से बातचीत करनी है। दरबारियों के आने का बड़ा फाटक तुरंत खोल दिया जाये और हांका देकर दरबारियों को मेरे सामने लाया जाये।" जार्ज फिर चुप्पी साधे रहे, तो दिल्ली दरबार ने गुस्से में आकर अपनी २१वीं सदी वाली चाबुक निकाल ली। चाबुक देखकर जार्ज की बोटी-बोटी कांपने लगी और वह गिड़गिड़ा कर पैरों पर गिर गये, "सर, दो घंटे से दरबार का बड़ा फाटक खुला हुआ है। लेकिन एक भी दरबारी वहां नहीं दिखायी पड़ रहा है। सारे वीआईपी इलाके में हांका भी लगवा दिया गया। लेकिन हक्कारे खाली हाथ ही लौट आये। एक भी दरबारी नहीं मिला।" दिल्ली दरबार गरजे, "ये सारे दरबारी आखिर कहां गये?" जार्ज ने कमर से दोहरे होकर अर्ज किया, "हुजूर, सारे दरबारी पिकनिक मनाने इलाहाबाद गये हुए हैं।" दिल्ली दरबार ने चाबुक जमीन पर फेंक कर खुशी का इजहार किया, "वैरी गुड, मुझे खुशी हुई कि हमारे दरबारियों ने 'लाइफ को इनज्वाय' करने की सीख को पकड़ लिया। मेरी ओर से मेरे दरबारियों को इलाहाबाद में बधाई का संदेश दिया जाये।" दिल्ली दरबार खुशी से 'राक-एन-रोल' करने लगे, तो पीछे से मुस्कानी मेकअप मलकर केसरी और गुलाम आ गये। जब दिल्ली दरबार ने अपना 'राक-एन-रोल' बंद नहीं किया, तो पहले सीताराम केसरी और उसके बाद गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल हो गये। लेकिन थोड़ी ही देर में केसरी और गुलाम ने एक दूसरे को दुलत्ती मार-मार कर फर्श पर धराशायी कर दिया। जार्ज ने लपक कर दिल्ली दरबार के नथुनों में 'लाफिंग गैस' का सिलेंडर घुसेड़ दिया। जब दिल्ली दरबार छींक मार-मारकर बेतहाशा हंसने लगे, तो गुलाम-केसरी फर्श से उठकर 'हंसी' में शामिल हो लिये। लेकिन कुछ ही देर में दोनों के मुंह से झाग निकलने लगे, क्योंकि मुकाबला 'लाफिंग गैस' से था। केसरी ने तुरन्त सैम पित्रोदा को इशारा किया कि 'कंट्रोल रूम' से जवाबी हंसी का टेप बजाओ, नहीं तो हम लोगों के प्राण पखेरू हंसते-हंसते उड़ जायेंगे। सैम पित्रोदा को दया आ गयी और उन्होंने लपक कर कंट्रोल रूम में 'जवाबी हंसी' का टेप चालू कर दिया। पूरे दरबार में 'हंसी' और 'जवाबी हंसी' का अट्टहास गूंजने लगा।

गोरखपुर नरेश वीर बहादुर सिंह कच्छा-बनियान में घंटों से खड़े इस उधेड़-बुन में थे कि अट्टहास लगाकर दिल्ली दरबार की 'लाफिंग गैस' में शामिल हुआ जाये या दहाड़ मार कर रोने का साथ दिया जाये। आखिर में गोरखपुर नरेश की यही समझ में आया, "हंसने के दिन तो अब गये, रोने की दहाड़ ही ठीक रहेगी।" वह एक दर्जन उठक-बैठक लगाकर जब पसीने से लथ-पथ हुए, तो कसकर दहाड़ मार कर रोने लगे। रोने की दहाड़ सुनते ही जार्ज ने लपक कर दिल्ली दरबार के नथुनों में लगी 'लाफिंग गैस' के सिलेंडर को खींच लिया और उधर दूसरी ओर सैम पित्रोदा ने कंट्रोल रूम से 'जवाबी हंसी' का टेप 'आफ' कर दिया। अब पूरे दरबार में 'पिन ड्राप' खामोशी में केवल गोरखपुर नरेश की दहाड़ गूंज रही थी। सारा वातावरण स्तब्ध था।

केसरीजी ने अपनी धोती खोलकर गोरखपुर नरेश को नाक पोंछने को दे दी, तो गुलाम नबी आजाद ने अपनी तुर्की टोपी को उनके मुंह के नीचे इस लालच में कर दिया कि वीर बहादुर के आंसुओं से भी मोती ही गिरते हैं। दिल्ली दरबार ने गोरखपुर नरेश को पुचकारते हुए डपटा, "अरे मंत्रीजी, यह हाल कैसे हुआ? क्या राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुर्ता-पैजामा और टोपी छीन कर आपको कच्छा-बनियान में कर दिया?" वीर बहादुर सिंह के जवाब देने से पहले गुलाम नबी आजाद बोले, "सर, यह बहुत परेशान हैं। तांत्रिकों ने इनको कहा था कि नोटों की गड्डियां बिछाकर उस पर गहरी नींद लो, तो सारे संकट कट जायेंगे। पिछले दिनों इनके पलंग में आग लग गयी। सब कुछ जल गया। केवल यह कच्छा-बनियान ही बची है।"

गुलाम नबी ने जैसे ही अपना वाक्य पूरा किया, तो वीर बहादुर दहाड़ मार कर रोने लगे। दिल्ली दरबार पसीजे और वीर बहादुर की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षित कोष से अनुदान देने की घोषणा करें कि उसके पहले इलाहाबाद से संतोष मोहन देव का दूरभाष वसंत साठे लेकर हाजिर हो गये, "हुजूर, इलाहाबाद में हमारी पिकनिक पार्टी पर राजा मांडा ने पूरे विरोधी दलों के साथ हमला बोल दिया है। संतोष मोहन देव वहां से भागने की फिराक में हैं।" दिल्ली दरबार बुरी तरह गरजे, "हमारे दरबारियों की पिकनिक पार्टी पर हमला राष्ट्र द्रोह है। इसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा। संतोष मोहन देव को कहो कि हम कुमुक भेज रहे हैं। भागने का विचार वह अपने मन से निकाल दें।" सारे दिल्ली दरबार का वातावरण गमगीन हो उठा। लोग सोचने के लिए बाल खुजलाने लगे। जब लोगों के भेजे में कुछ नहीं आया, तो सैम पित्रोदा ने तुरंत सारे लोगों के सिरों पर सोचने की मशीन बांध दी। मशीन को 'आन' करते जब तरंगे भेजे में घुसने लगीं, तो दरबारी फुदकने लगे।

थोड़ी ही देर में सीताराम केसरी ने सोचने की मशीन का चोंगा उतार कर फेंक दिया और चीख पड़े, "सर, मिल गया। मिल गया।" दिल्ली दरबार ने प्रश्नवाचक मुद्रा में केसरीजी की ओर देखा, "क्या मिल गया?" केसरीजी ने अपनी आवाज की 'पिच' कुछ शर्माते हुए कम कर दी, "हुजूर, हम लोग इलाहाबाद का चुनाव राम भरोसे छोड़ दें।"

दिल्ली दरबार ने अपनी भाव-भंगिमा में कोई परिवर्तन लाये बिना प्रश्न किया, "क्या मतलब! इलाहाबाद का चुनाव राम भरोसे छोड़ दिया जाये!" केसरीजी ने आगे अदब के साथ बढ़ते हुए कहा, "जी सरकार, वह अपने रामायण सीरियल का राम है न, वही अरुण गोविल-उसके जिम्मे इलाहाबाद का चुनाव छोड़ दिया जाये। अरुण गोविल राजा मांडा के ही नहीं, बल्कि पूरे विरोधी दलों के भूसा भर देगा।"

दिल्ली दरबार में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गयी। हर तरफ से उद्घोष-सा होने लगा: बोल श्री रामचंद्र की जय। पूरे दरबार में रामलीला जैसा वातावरण हो गया और सारे दरबारी रामलीला के पात्रों में परिवर्तित हो गये।

—दरबारी लाल

> **दिल्ली दरबार ने अपनी भाव-भंगिमा में कोई परिवर्तन लाये बिना प्रश्न किया, "क्या मतलब! इलाहाबाद का चुनाव राम भरोसे छोड़ दिया जाये!" केसरीजी ने आगे अदब के साथ बढ़ते हुए कहा, "जी सरकार, वह अपने रामायण सीरियल का राम है न, वही अरुण गोविल-उसके जिम्मे इलाहाबाद का चुनाव छोड़ दिया जाये। अरुण गोविल राजा मांडा के ही नहीं, बल्कि पूरे विरोधी दलों के भूसा भर देगा।"**

फेल होने का रिकार्ड

सोनीपत (हरियाणा) में एक सरकारी हाईस्कूल और दो प्राइवेट हाईस्कूल ऐसे भी हैं, जिनके सारे विद्यार्थी हरियाणा स्कूल शिक्षां बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में फेल हो गये और करीब २० हाईस्कूल ऐसे भी हैं, जिनमें सिर्फ एक-एक छात्र उत्तीर्ण हुआ है।

पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'वर्ल्ड वाच संस्थान' द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार विश्व का पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि इसे ठीक-ठाक रखने के लिए प्रतिवर्ष १५० बिलियन डालर का (करीब २१० अरब रुपए) खर्च आयेगा।

पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर की ३० मीटर परिधि में आनेवाली सभी इमारतों को अधिग्रहीत करने का फैसला किया है, जिन्हें गिराकर, उस क्षेत्र का सुंदरीकरण किया जायेगा। इस निमित्त ११० करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनायी गयी है।

भारत को इस वर्ष ४० लाख टन गेहूं का आयात करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अन्न के भण्डार में गेहूं की कमी हो गयी है। सरकार के पास इस समय ९४ लाख ३० हजार टन अन्न का भण्डार है, जिसमें १४ लाख ५० हजार टन गेहूं, ७८ लाख टन चावल तथा शेष मोटा अनाज है। सरकारी मापदंड के अनुसार सरकार के भण्डार में प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल को १६५ लाख टन तथा एक जुलाई को २१४ लाख टन अनाज रहना चाहिए।

खगोलशास्त्रियों की निगाहें पृथ्वी के सर्वाधिक निकट के सुपरनोवा तारे पर टिकी हुई हैं, जो चार सौ वर्षों बाद भारी विस्फोट के साथ न्यूट्रान तारे में बदल जायेगा। यह पहला अवसर है, जब पृथ्वी पर एक तारे के जन्म का रिकार्ड रखा जा रहा है।

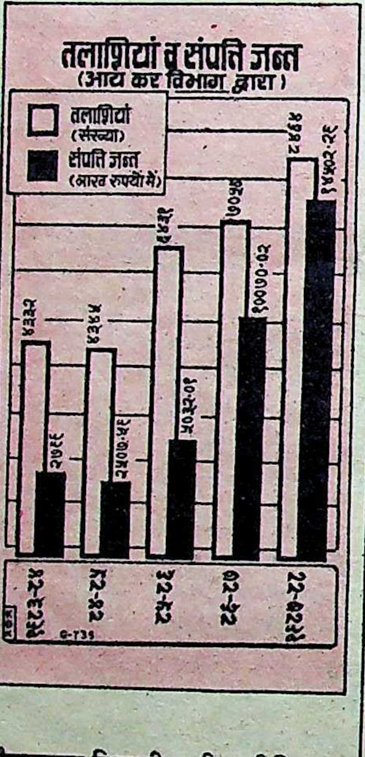

हैदराबाद-निवासी श्री श्रीनिवास भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो अमरीका में टेक्सास राज्य के एक शहर हालीवुड पार्क के मेयर चुने गये हैं।

बंगलादेश में इस्लाम को राजधर्म बनाने के लिए प्रस्तुत बंगलादेश के संविधान संशोधन विधेयक का वहां के विभिन्न क्षेत्रों के तीन सौ बुद्धिजीवियों ने घोर विरोध किया है।

राजस्थान में भीषण गर्मी से मरनेवालों की संख्या दो सौ से ऊपर पहुंच चुकी है। पूरे देश में लू से मरनेवालों की संख्या चार सौ को पार कर गयी है।

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के एक अभियुक्त २४ वर्षीय सतवंत सिंह का अमृतसर जिले के जट्टन गांव की सुरिंदर कौर से विवाह हो गया है। यह विवाह सतवंत सिंह की फोटो के साथ हुआ, क्योंकि वह इस समय तिहाड जेल में है।

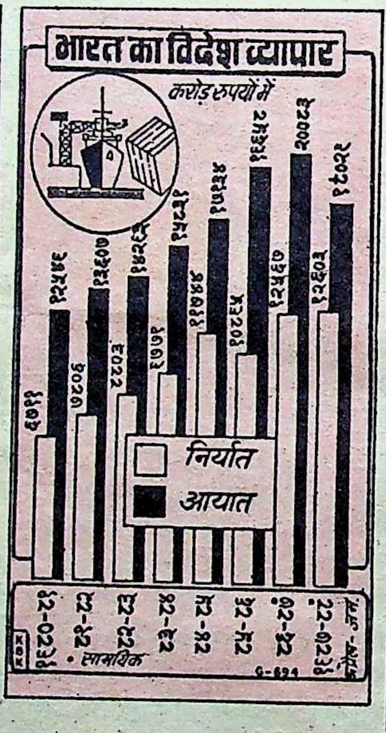

भारत सरकार ने परिवार नियोजन के अंतर्गत १९८७-८८ के लिए ६० लाख स्त्री-पुरुषों का आपरेशन करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह आंकड़ा ४८ लाख ९० हजार तक ही पहुंच सका। भारत में अभी तक २ करोड़ २५ लाख स्त्री-पुरुष परिवार नियोजन आपरेशन करा चुके हैं। भारत सरकार ने वर्ष १९८८-८९ के लिए ५७ लाख ६० हजार और १९८०-९० के लिए ५७ लाख, ९० हजार आपरेशनों का लक्ष्य रखा है।

पंजाब और उत्तर प्रदेश ने ही परिवार नियोजन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत से अधिक पूरा किया। सबसे कम (२५ से ५० प्रतिशत) परिवार नियोजन असम तथा जम्मू और कश्मीर में हुए।

विश्व में वैज्ञानिकों का मत है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई के कारण पृथ्वी का तापमान आगामी ३०-४० वर्षों में डेढ़ से साढ़े चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा। इसके असर से समुद्र का फैलाव होगा और जलस्तर कम-से-कम एक मीटर ऊंचा उठ जायेगा जिसके फलस्वरूप प्रशांत व अंध महासागर के अनेक द्वीप समुद्र में डूब जायेंगे। अकेले बंगलादेश व मिस्र में ही क्रमशः डेढ़ और एक करोड़ लोग मारे जायेंगे।

जो व्यक्ति तीन मीटर की दूरी से भी किसी के हाथों की उंगलियां नहीं गिन सकता, उसे 'अंधा' कहा जाता है। दुनिया में एक अनुमान के अनुसार इस समय अंधों की संख्या पौने तीन से साढ़े चार करोड़ है।

तमिल टाइगर्स को काबू करने गयी भारतीय शांति सेना के जवानों ने भारत लौटना शुरू कर दिया है। ७ जून को तीन हजार सैनिक वापस लौटे। श्रीलंका में इस समय पचास हजार से अधिक भारतीय सैनिक हैं। श्रीलंका में की गयी सैन्य कार्यवाहियों में ४६० भारतीय सैनिक शहीद हुए तथा १४५० तमिल टाइगर्स मारे गये।

श्रीलंका में आंतरिक युद्ध के माहौल में २ जून को हुए चुनावों में ५ प्रतिशत मतदान हुआ। जयवर्धने की यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने पश्चिमी परिषद में १०२ सीटों में से ५२ तथा केंद्रीय परिषद में ५६ सीटों में से ३५ सीटें जीत लीं। कुल ३६ लाख मतदाताओं में से २०.३ लाख ने मतदान में हिस्सा लिया।

कांग्रेस-इ ने 'साप्ताहिक कांग्रेस' नाम से अपने एक मुखपत्र का अंग्रेजी व हिंदी में प्रकाशन तीन जून से प्रारंभ कर दिया है। मूल सामग्री अंग्रेजी में तैयार की जायेगी। हिंदी संस्करण अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद होगा। 'कांग्रेस' मुखपत्र के संपादक गुलाम नबी आजाद हैं।

—संयोजन : विनोद मिश्र

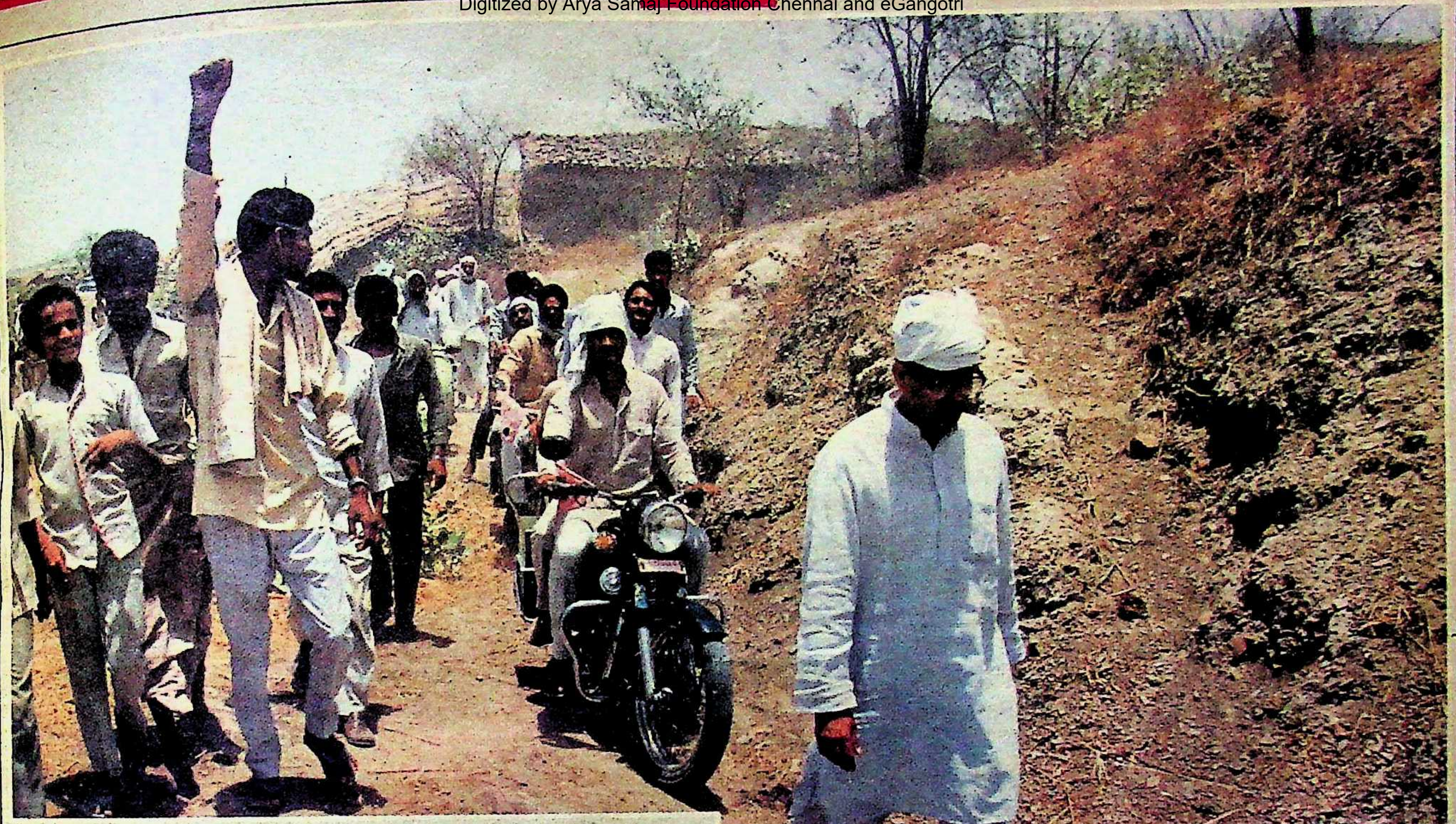

इलाहाबाद की जन अदालत में इंसाफ की गुहार : तपती धूप में गांव-गांव, डगर-डगर जन सम्पर्क करते राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

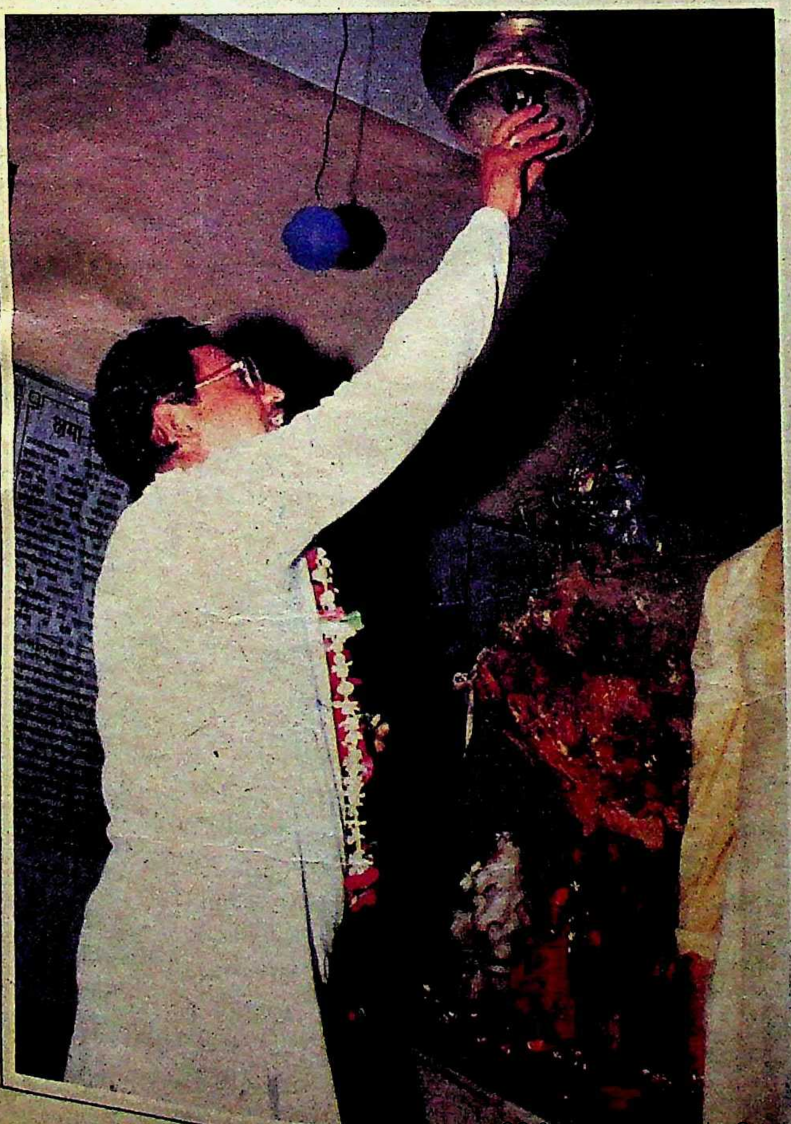

देवी ने भी कल्याण नहीं किया : कल्याणी देवी के मंदिर में स्तुति करते सुनील शास्त्री

छाया : मनमोहन शर्मा

एनटीआर की कुमुक : आंध्र से आयी 'यलो ब्रिगेड'

छाया : मनमोहन शर्मा

वीपी को जिताओ : आंध्र के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव देहात की एक चुनाव सभा में

छाया : मनमोहन शर्मा

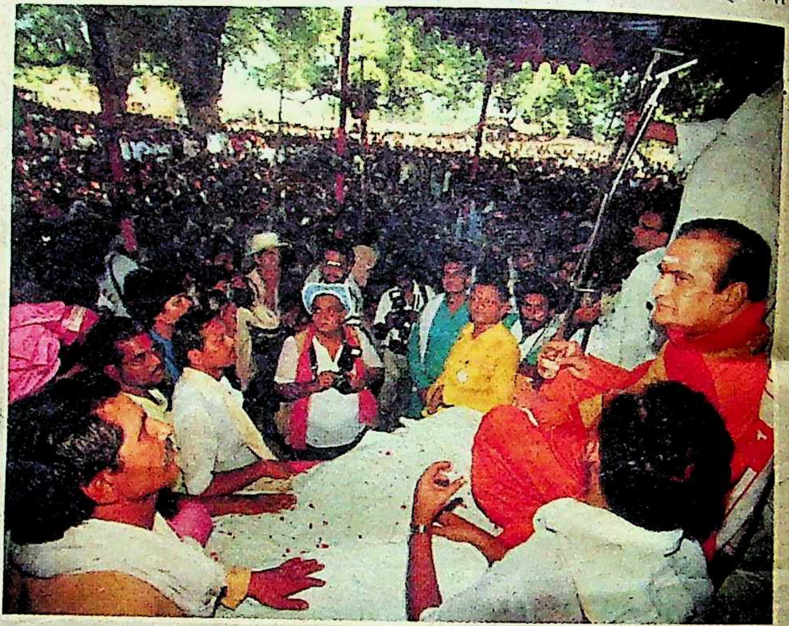

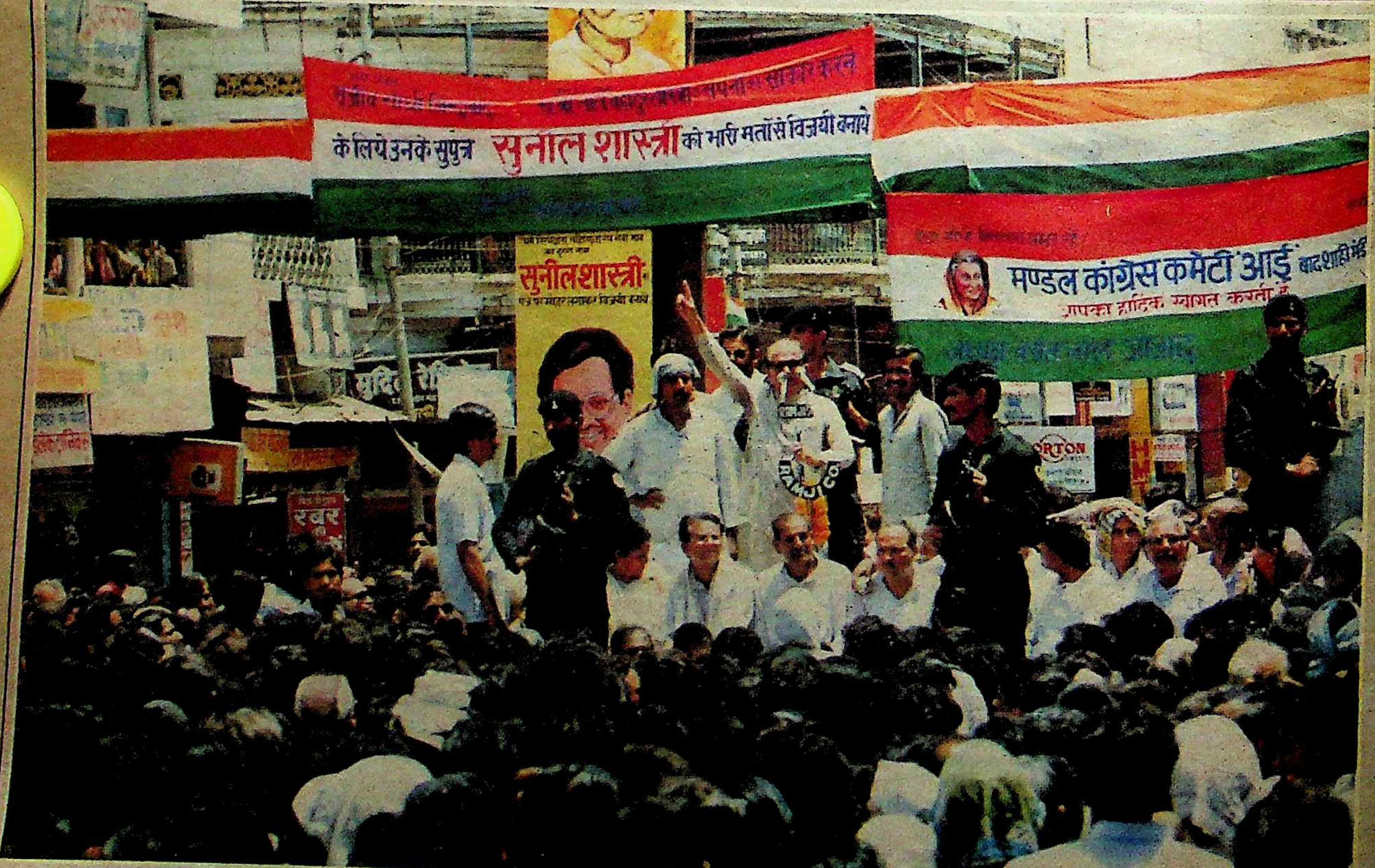
के लिये उनके सुपुत्र सुनील शास्त्री को भारी मतों से विजयी बनाये
सुनीलशास्त्री
मण्डल कांग्रेस कमेटी आई बादशाही मंडी
आपका हार्दिक स्वागत करती है

बेअसर : कमाण्डोज की निगहबानी में इलाहाबाद में कांग्रेस-इ का चुनाव प्रचार करते दिल्ली के बेताज बादशाह एचकेएल भगत

छाया : राजेन्द्र कुमार

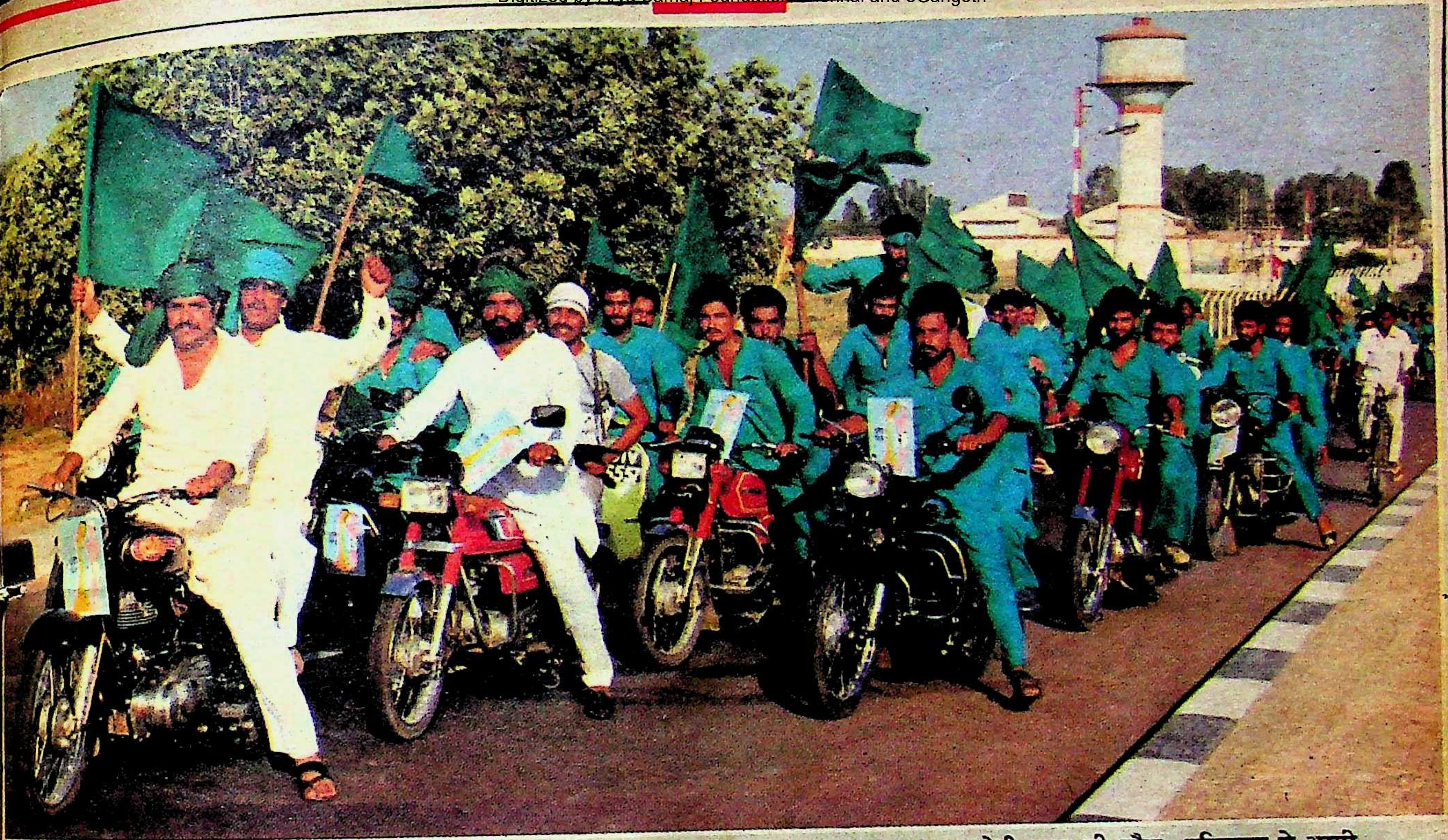

देवी लाल की फौज: हरियाणा से आयी बहुचर्चित 'ग्रीन ब्रिगेड'

छाया : वसीमुल हक

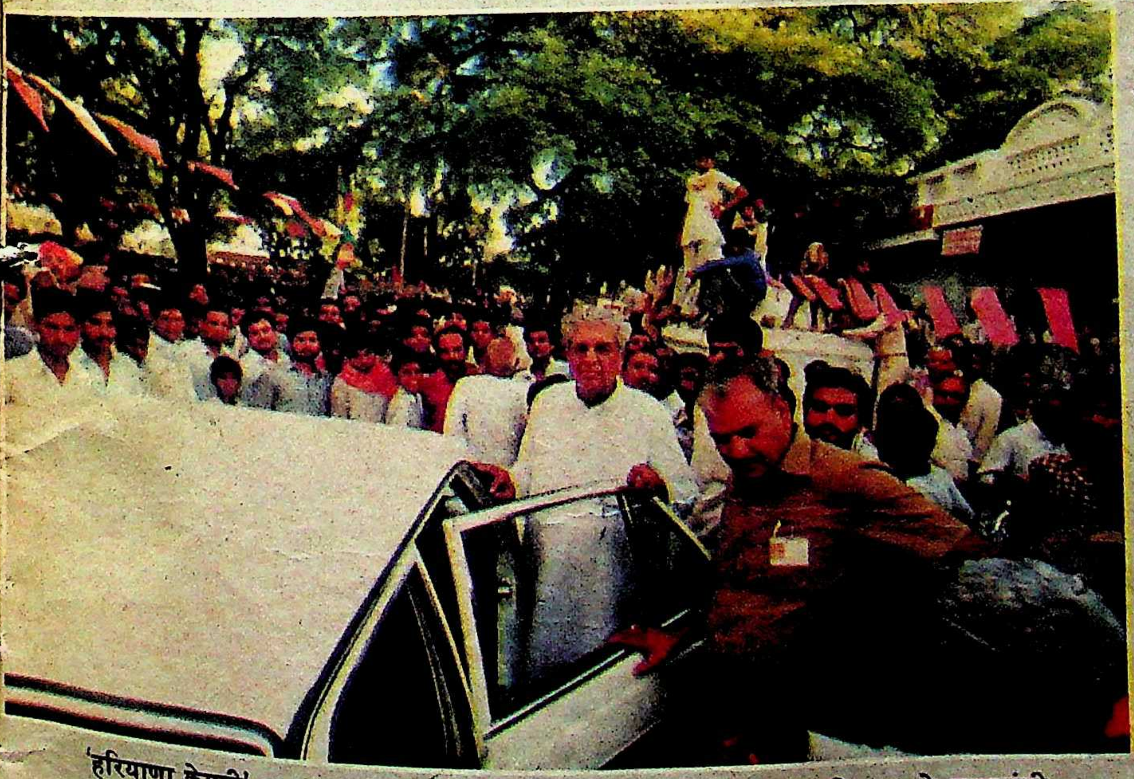

'हरियाणा केसरी' इलाहाबाद में: वीपी सिंह का मनोबल बढ़ाने आये हरियाणा के मुख्यमंत्री देवी लाल द्वारा चुनाव प्रचार

छाया : मनमोहन शर्मा

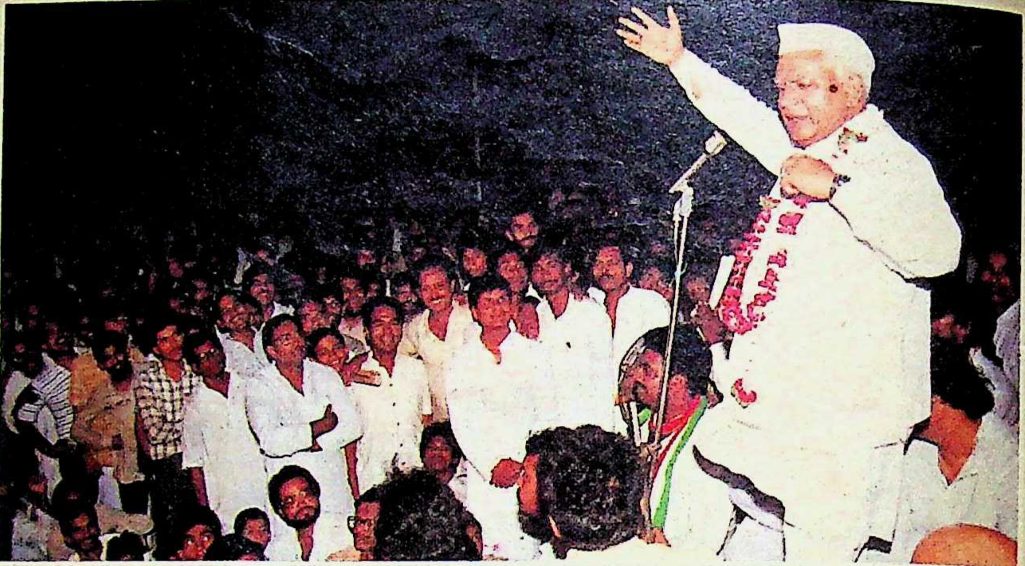

कांग्रेस-इ का कोई विकल्प नहीं : केंद्रीय वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी की इलाहाबाद की एक चुनाव सभा में गर्जना

छाया : मनमोहन शर्मा

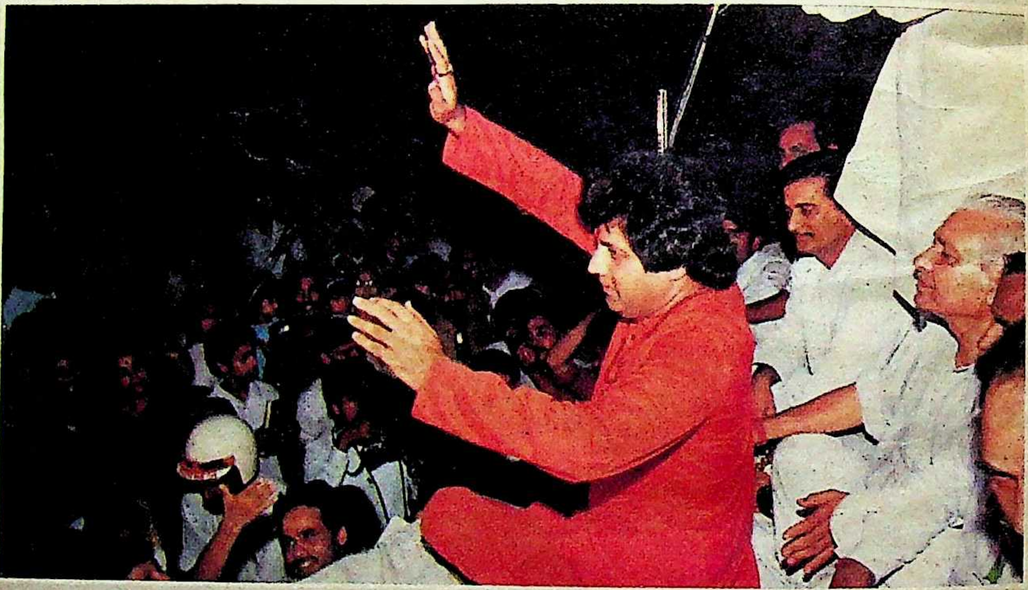

'राम' जो काम नहीं आये : रामायण सीरियल में राम का अभिनय करनेवाले अरुण गोविल सुनील शास्त्री के चुनाव प्रचार में इलाहाबादवासियों को आशीर्वाद देते हुए

छाया : राजेन्द्र कुमार

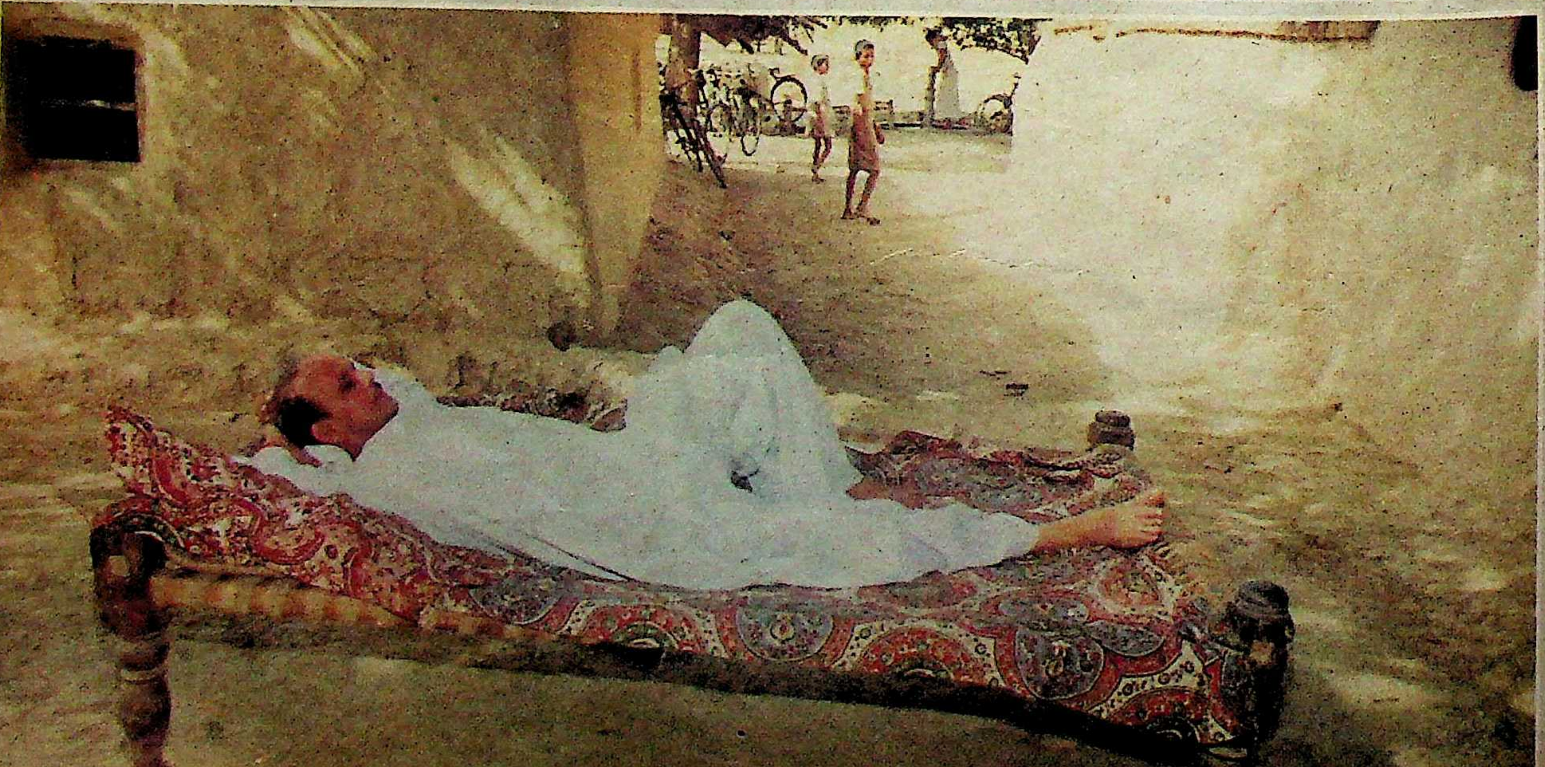

'राजा नहीं फकीर हैं' : चुनाव प्रचार के दौरान थकान मिटाते राजा

छाया : मनमोहन शर्मा

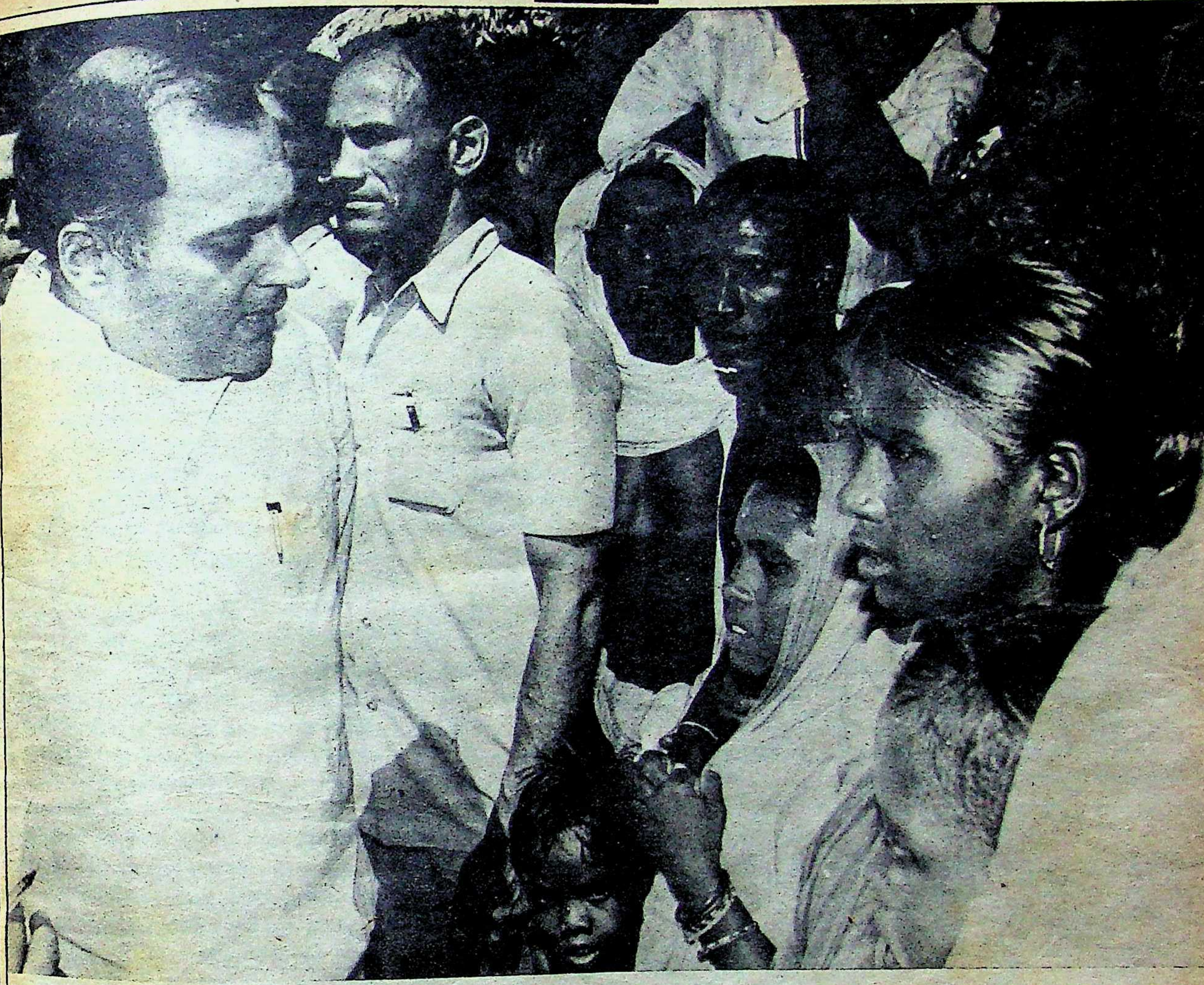

आदिवासी वोटों पर नजर : पुरलिया व बांकुरा के आदिवासियों के बीच राजीव गांधी

आदिवासियों को अपना बनाने की राजनीति

राजीव गांधी सत्ता संभालने के बाद से देश के आदिवासी अंचलों में खास दिलचस्पी लेकर दौरा करते रहे हैं। आनेवाले दिनों में असम से लेकर मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा व अन्य हिस्सों में अलगाववादी मुहिम में मसरूफ आदिवासियों को क्या राजीव अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पायेंगे ?

विगत कई दशकों से आदिवासी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जोकि किसी भी प्रांत की राजनीति में वे एक नन्ही हैसियत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में नहीं आ सके। राष्ट्रीय राजनीति में न पहुंच पाना ही शायद यह कारण है कि चाहे कांग्रेस शासित प्रांत बिहार, म०प्र० व उड़ीसा हो या असम गण परिषद शासित प्रफुल्ल महंत की असम में गैर कांग्रेसी सरकार—इन सभी प्रांतों के आदिवासी अलग प्रांत की विस्फोटक गुहार करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के आदिवासीबहुल क्षेत्र को मिलाकर अलग झारखंड प्रांत का आंदोलन विगत दो-तीन दशकों से कभी धीमे-तो-कभी तेज चलता ही रहा है। इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए ही गुजरे दशकों में कई आदिवासी संगठन बने और फिर अस्तित्वहीन भी हो गये या आखिरकार कांग्रेस

में मिल गये। पर आदिवासी संगठनों के बनने का क्रम टूटा नहीं। बिहार में एक झारखंड पार्टी टूटी या कांग्रेस में मिल गयी, तो दूसरी झारखंड पार्टी बन गयी। वह भी खतम हुई, तो 'झारखंड मुक्ति मोर्चा' जैसा राजनीतिक दल बन गया। 'झारखंड मुक्ति मोर्चा' का तेवर भी जब ठंडा पड़ा गया, तो 'झारखंड समन्वय समिति' या फिर 'आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन' (आजसू) जैसे लड़ाकू छात्र संगठनों की पैदाइश हो गयी। जाहिर था कि कई आदिवासी नेता भी बने और बिगड़े।

बोडो प्रांत की मांग : इसी तरह, असम में भी हुआ। असम के आदिवासियों ने अलग 'बोडो प्रांत' की मांग को लेकर पहले १५ फरवरी, १९६७ को 'आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' (एबीएसयू) की स्थापना की और साथ ही २७ फरवरी, १९६७ को एक आदिवासी राजनीतिक दल 'प्लेंस ट्रायबल कांउसिल ऑफ असम' (पीटीसीए) का गठन किया। पर १९७७ में पीटीसीए और एबीएसयू में इसलिए मतांतर हो गया, क्योंकि पीटीसीए अलग बोडो प्रांत की मांग से मुकर गया। जनता पार्टी की लहर में जनता पार्टी से तालमेल कर पीटीसीए के एक प्रमुख नेता समर ब्रह्म चौधरी विधायक हो गये और दूसरे नेता चरण नर्जरी सांसद हो गये। समर ब्रह्म उस समय असम की जनता सरकार में मंत्री भी हुए थे। फिर जनता सरकार जब असम में गिर गयी, तो केशब गोगोई की अल्पजीवी कांग्रेस सरकार में भी समर ब्रह्म शरीक हो गये। बाद में फिर असम गण परिषद से तालमेल कर वह सांसद हो गये। इस तरह आलबोडो स्टूडेंट्स यूनियन के लड़ाकू बोडो आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि पीटीसीए के नेताओं ने निजी लाभ के चक्कर में आदिवासी आंदोलन का सौदा कर लिया। फिर भी वे हारे नहीं और एक समानांतर पीटीसीए (प्रोग्रेसिव) की स्थापना २२ मई, १९७९ को कर डाली। अब पीटीसीए (प्रोग्रेसिव) और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने संयुक्त रूप से 'मिशिग बोडो लैंड' की मांग उठायी। फिर बाद में १९ अप्रैल, १९८४ को पीटीसीए (प्रोग्रेसिव) को भंग कर एक नये आदिवासी राजनीतिक संगठन 'यूनाइटेड ट्रायबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट' (यूटीएनएलएफ) की नींव डाली गयी, जिसके अध्यक्ष हुए विधायक बिनय बासुमात्री। बिनय पहले नेवी में अफसर थे। लिहाजा, अब पीटीसीए जहां असम के सत्ताधारी दल असम गण परिषद् के पीछे भक्तिभाव से जुड़ी है, वहीं एबीएसयू और यूटीएनएलएफ संयुक्त रूप से अलग 'बोडो लैंड' के सवाल पर विस्फोटक रूप से मुखर हैं। इन दोनों संगठनों के नेताओं का कहना है कि असम की मौजूदा सरकार में आदिवासियों की अस्मिता का बचाव असंभव है, इसलिए हमें अलग आदिवासी प्रांत 'बोडोलैंड' चाहिए ही। इस तरह जहां बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा व बंगाल के आदिवासीबहुल जिले को मिलाकर अलग झारखंड प्रांत की लड़ाई लड़नेवाले आदिवासी संगठनों में विसंगतियां उभरीं, ठीक उसी तरह असम में 'बोडोलैंड' की मांग को लेकर जन्मे आदिवासी संगठन फूट व टकराव के रोग से अछूते न रह सके।

विद्रोही तेवर : तीर-धनुष लिये आदिवासी

आखिर असम के आदिवासी बोडोलैंड के सवाल पर क्यों मुखर होकर आंदोलित हैं? आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के मुताबिक असम में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास असम की इस वर्तमान सरकार के तहत हरगिज नहीं हो सकता। इस सरकार में आदिवासी बुरी तरह असुरक्षित हैं।

असम में सिर्फ बोडो जाति के आदिवासियों की आबादी चालीस लाख से ऊपर है। इसके अलावा आदिवासियों में मिशिग की जनसंख्या लगभग पांच लाख है, राभास डेढ़ लाख के करीब हैं, सोनवाल एक लाख, कर्बी चालीस हजार के आसपास और लालुंग लगभग साठ हजार। लिहाजा अलग बोडो प्रांत 'यूनियन टेरिटरी' की हैसियत का मांगा जा रहा है। असम का कुल क्षेत्रफल ७८,५२३ वर्ग किलोमीटर है और इसमें से २५,४७८.१ वर्ग किलोमीटर अलग बोडो लैंड के लिए मांगा जा रहा है। आदिवासी आंदोलनकारियों का नारा है—'असम बांटो फिफ्टी-फिफ्टी!' इस नारे से नाराज असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने अपनी कई सभाओं में कहा कि असम कोई खाने-पीने की चीज तो है नहीं, जो उसे आधा-आधा, बांट दिया जाये। पहले ही असम कई बार बंट चुका है।

असम के कोकराझाड़ जिले व उदलपुरी क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत ने अपनी सरकार में राजस्व मंत्री थानेश्वर बोरो जो खुद आदिवासी हैं, को कोकराझाड़ जिले की समस्या से निपटने के लिए तैनात किया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री अतुलबोरा और शिक्षा मंत्री बृंदाबन गोस्वामी को दारंग जिले के उदलपुरी सब डिवीजन की आदिवासी—आग को शांत करने का जिम्मा सौंपा है। पर इस आग को शांत करना असंभव लगता है। असम गण परिषद् के दो प्रवक्ताओं केजी भट्टाचार्य व चाणक्य दास ने एक बयान जारी कर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके लुइस इसलारी व यीटीएनएलएफ के बिनय बासुमात्री आदिवासी अंचल में अलगाववादी प्रवृत्ति को हवा दे रहे हैं। असम गण परिषद् वालों ने आरोप यह भी लगाया है कि इस आंदोलन के पीछे ईसाई मिशनरियां भी सक्रिय हैं।

पुलिसिया जुल्म : पर बोडोलैंड की मांग को लेकर असम के कोकराझाड़ जिले व उदलगुरी क्षेत्र में विद्रोह का परचम लहरा रहे आदिवादियों का गुस्सा बेमानी नहीं है। सही मायने में ये दोनों क्षेत्र पुलिस जुल्म व दमन तथा सरकारी उपेक्षा से तबाह रहे हैं। कोकराझाड़ जिले के तहत ही २७ जनवरी की आधी रात भूमका गांव (नंबर बारह) में १२-१५ साल की मासूम आदिवासी लड़कियों थोर्ली, लोलिता, सुनीला, जयमती नर्जरी आदि दसेक लड़कियों के सग सेरफांगुरी आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन के सशस्त्र पुलिस दल ने अपना मुंह काला किया। कोकराझाड़ के भूमका गांव की निरीह आदिवासी लड़कियों के संग हुए बलात्कार के सवाल पर 'अखिल असम आदिवासी महिला कल्याण संघ' की जुझारू अध्यक्ष, प्रोमिला रानी ब्रह्मा ने आरक्षी

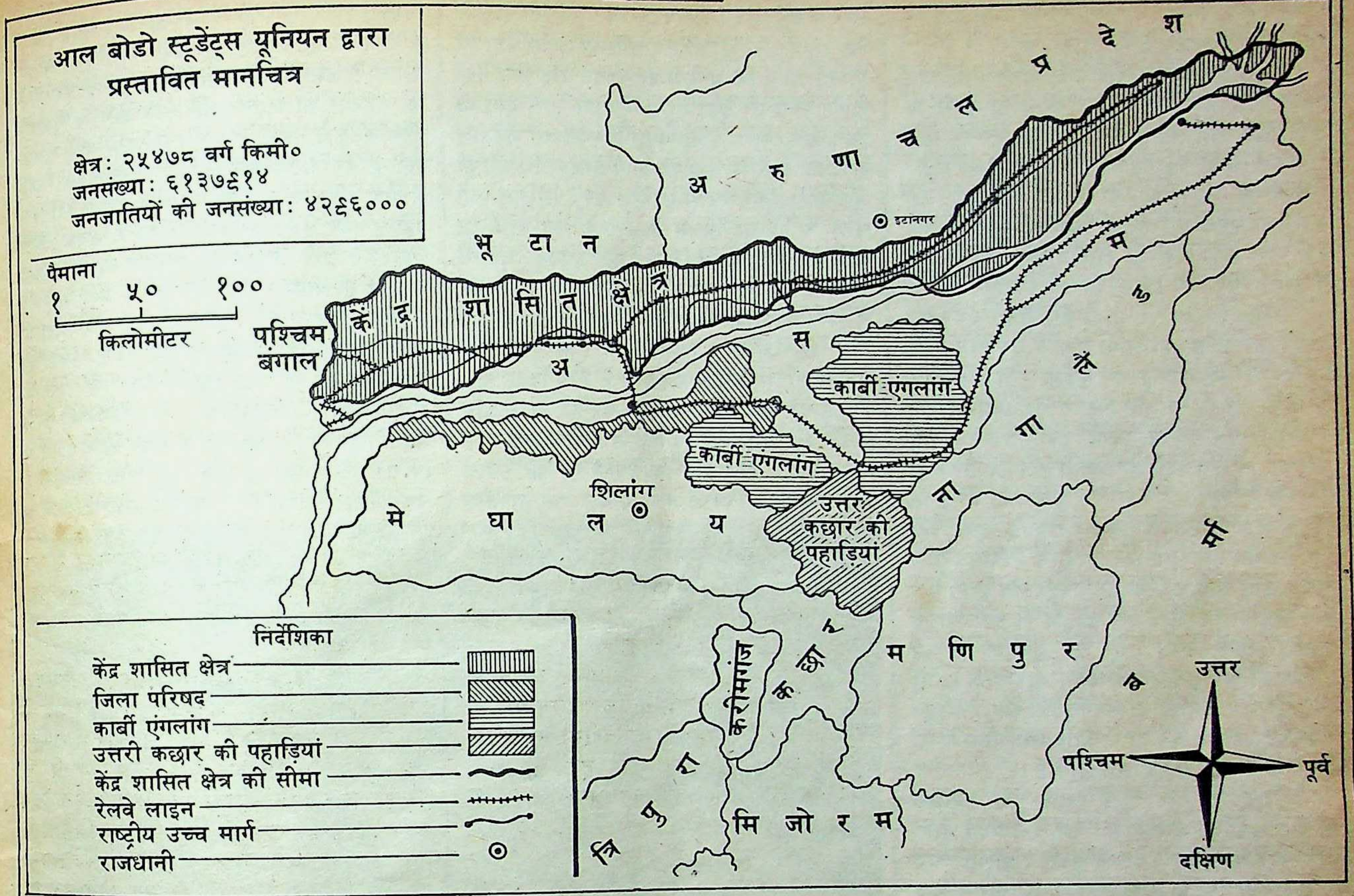
आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा प्रस्तावित मानचित्र
क्षेत्र: २५४७८ वर्ग किमी०
जनसंख्या: ६१३७६१४
जनजातियों की जनसंख्या: ४२६६०००
पैमाना
१
५०
१००
किलोमीटर
अरुणाचल प्रदेश
इटानगर
भूटान
पश्चिम बंगाल
केंद्र शासित क्षेत्र
असम
कार्बी एंगलांग
कार्बी एंगलांग
उत्तर कछार की पहाड़ियां
शिलांग
मेघालय
नागालैंड
मणिपुर
कछार
करीमगंज
त्रिपुरा
मिजोरम
म्यांमार
बर्मा
उत्तर
पश्चिम
पूर्व
दक्षिण
निर्देशिका
केंद्र शासित क्षेत्र
जिला परिषद
कार्बी एंगलांग
उत्तरी कछार की पहाड़ियां
केंद्र शासित क्षेत्र की सीमा
रेलवे लाइन
राष्ट्रीय उच्च मार्ग
राजधानी

अलगाव पर उतारू : बोडोलैंड क्षेत्र का प्रस्तावित मानचित्र

अधीक्षक, डिप्टी कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक को हादसे का पूरा विवरण देकर कार्रवाई की मांग की। एक डेढ़ महीने तक तो असम की सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि भूमका गांव में आदिवासी लड़कियों के संग पुलिस ने सामूहिक बलात्कार किया। पर बाद में काफी हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों को १ मार्च, १६८८ को महज निलंबित किया गया, जबकि आदिवासी संगठन मांग यह कर रहे थे कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को मुअत्तल कर जेल भेजा जाये। प्रोमिला रानी ब्रह्मा तो कहती हैं, "यहां आदिवासी औरतों की अस्मत हर पल असुरक्षित है।" इसलिए चाहे वह मध्यप्रदेश, बिहार या उड़ीसा हो या फिर आंध्र प्रदेश और असम कहीं भी आदिवासियों का जीवन सम्मानित या सुरक्षित नहीं है। इस बात से आदिवासियों की नयी लड़ाकू पीढ़ी विचलित है। यों आदिवासी कल्याण के नाम पर असम में ट्रायबल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, ट्रायबल डेवलपमेंट अथारिटी, इंटेग्रेटेड ट्रायबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सरीखी बहुतेरी सरकारी एजेंसियां हैं, पर अधिकांश दिखावे के लिए। असम में ६५-७० प्रतिशत आदिवासी बिलकुल बेजमीन हैं। असम के आदिवासी क्षेत्र में लगभग दो लाख तेरह हजार चालीस बीघा जमीन गैरआदिवासियों ने कब्जा कर रखा है। पर सरकार इस सबके लिए तनिक भी परेशान नहीं है। नतीजतन, आदिवासियों के मन में यह बात जम गयी है कि प्रफुल्ल महंत को भी उनकी तबाहियों से कोई लेना-देना नहीं है। लिहाजा, 'असम बांटो—फिफ्टी-फिफ्टी' का नारा बुलंद हो रहा है।

कांग्रेस से लगाव : झारखंड मुक्तिमोर्चा के अध्यक्ष शीबू सोरेन

कोंडापल्ली सीतारमैया का गुस्सा : लगभग ऐसा ही आक्रोश आंध्रप्रदेश के आदिवासियों में है। आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले के घने जंगल में रहनेवाले आदिवासियों के मन में व्यापक उत्तेजना है। कोंडापल्ली सीतारमैया जैसे नक्सली नेता जिन्होंने पिछले दिनों आंध्रप्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का अपहरण कर लिया था, नाराज आदिवासियों को संगठित करने की मुहिम में मसरूफ हैं। कोंडापल्ली सीतारमैया द्वारा अपहृत पूर्वी गोदावरी के जिलाधीश एमवीएमसी शास्त्री जब नक्सलियों के चंगुल से छूटकर आये, तो उन्होंने कहा कि वे नक्सली आंध्र प्रदेश के शोषित आदिवासियों के दुख को लेकर ज्यादा मुखर थे। वाममोर्चा शासित पश्चिम बंगाल के भी आदिवासी चैन से नहीं बैठे हैं। बिहार के सिंहभूमि से ठीक सटा पश्चिम बंगाल का आदिवासीबहुल मिदनापुर क्षेत्र भी सुलग रहा है और अलग झारखंड आंदोलन में पंक्तिबद्ध हो रहा

है। बहरहाल, यह तो रही देश के गैर इंका-शासित प्रांतों के आदिवासियों की नाराजगी।

कांग्रेस-शासित प्रांतों में भी आदिवासी बहुत संतुष्ट नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आदिवासी जहां अपनी स्थिति से टूटे हुए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के आदिवासी भी सख्त गुस्से में हैं। उड़ीसा के मयूरभंज, बारीपदा, कोरापुट जैसे आदिवासीबहुल क्षेत्र में भी स्थिति विस्फोटक है। चाहे वह मयूरभंज के आदिवासी इंका सांसद सिद्धलाल मुरम हों या उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र के इंका सांसद गिरिधर गोमांगों हों, किसी को अपने क्षेत्र में सुलगते आदिवासियों से कोई लेना-देना नहीं है। गिरिधर गोमांगो हरदम केंद्रीय सत्ता के इर्दगिर्द ही घूमते रहे हैं, पर कोरापुट के आदिवासियों की दयनीय स्थिति में गोमांगो की राजनीतिक ताकत से रत्ती भर भी शायद ही कमी आयी हो। उड़ीसा के ही सुंदरगंढ़ के इंका सांसद मौरिस कुजूर को भी अपने क्षेत्र के आदिवासियों के दुख-दर्द से कोई वास्ता नहीं है। फिर गुजरात के आदिवासीबहुल क्षेत्र मांडवी के सांसद छीतू भाई गामित हों या गुजरात के ही एक अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्र दोहाद के इंका सांसद सोमजी भाई डामोर हों या गुजरात के ही आदिवासी क्षेत्र बलसाड के उत्तम भाई पटेल हों या फिर पश्चिम बंगाल के आदिवासी सांसद पीयूष टिर्की हों—किसी को अपने आदिवासी समाज की व्यथा से दूर-दूर का वास्ता नहीं है।

महाराष्ट्र में ६२ लाख से अधिक आदिवासियों की आबादी है। जमीन से खदेड़े जाने, अपनी बहू-बेटियों की अस्मत लुटने व पुलिस दमन का दुख महाराष्ट्र के आदिवासियों को व्यथित किए हुए है। डीवी शिगड़ा महाराष्ट्र के ठाणा जिले के डहाणू क्षेत्र से आदिवासी इंका सांसद हैं। इनके पूर्व मार्क्सवादी लहाणुशिडवा इस क्षेत्र से सांसद थे। आदिवासी क्षेत्र डहाणू में कातकारी, वार्ली, मल्लारकोई आदिवासी बसते हैं। सांसद शिगड़ा खुद वार्ली हैं। शिगड़ा के मुताबिक इस क्षेत्र के आदिवासियों में सबसे बुरी दशा कातकारियों की है, जिनके पास न तो एकाध एकड़ खेत ही है, न ही आजीविका का कोई अन्य साधन। महाराष्ट्र में आदिवासियों के लिए २२ विधानसभाई क्षेत्र सुरक्षित हैं, जिनमें १६-१७ इंका के ही आदिवासी विधायक हैं और चारों संसदीय आदिवासी क्षेत्र पर भी इंका का ही कब्जा है। पर महाराष्ट्र में भी इंका के आदिवासी प्रतिनिधियों ने कभी अपने आदिवासी बंधुओं की सही खोज खबर नहीं ली। मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, झाबुआ, शहडोल, धार, सीधी, बस्तर और कांकेर में भी आदिवासी सुखी नहीं हैं। अलग झारखंड के आंदोलन में बिहार के सीमावर्ती मध्यप्रदेश के क्षेत्रों के आदिवासी कमोबेश सक्रिय हैं। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी बस्तर जिले में है और फिर नबर आता है, सरगुजा का। सरगुजा के वर्तमान इंका सांसद लाल विजय प्रताप सिंह राजगोंड हैं। लाल विजय पहले आदिवासीबहुल विधानसभाई क्षेत्र सूरजपुर से विधायक थे। संसद में उनका यह पहला मौका है। पर सरगुजा क्षेत्र के विकास में इन इंका प्रतिनिधियों की उदासीनता का ही नतीजा है कि भाजपा यहां अपने पांव फैला रही है। रायगढ़ की इंका सांसद कुमारी पुष्पा देवी या फिर केंद्रीय सत्ता में महत्वपूर्ण हैसियतवाले शहडोल के सांसद दलबीर सिंह भी अपने चिथड़ा-चिथड़ा हो चुके आदिवासी बंधुओं को भूल गये। इसलिए चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के—सबके सब राजनेता आदिवासियों से विमुख रहे हैं, इसका अहसास कमोबेश-आदिवासियों को है। नतीजतन, लंबे अरसे से ठंडा जंगल तेजी से सुर्ख हो रहा है, जलने लगा है।

आदिवासी राजनीतिक परिदृश्य में आदिवासी गांवों में विशेष रुचि के साथ विगत कुछ वर्षों से खुद कार या जीप ड्राइव कर घूम रहे राजीव गांधी क्या आगामी चुनाव में आदिवासी वोट बटोर लेंगे? राजनीति विश्लेषकों का यह कयास बेदम नहीं है। विपक्षी दलों में बस एक भारतीय जनता पार्टी है, जो थोड़ी-बहुत आदिवासियों के बीच टिमटिमा रही है। आदिवासी हिंदुत्व की भावना से ओत-प्रोत हैं। शायद यह भी एक कारण है कि भाजपा को आदिवासी अपने क्षेत्र में घुसकर काम करने दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ चाहे जनता पार्टी हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी या लोकदल-किसी के पास 'शो पीस' के लिए भी कोई आदिवासी नेता नहीं है और न ही आदिवासी क्षेत्र मे उनका कोई दखल है। राजीव गांधी हिंदू वोट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ के दंगों के बाद मुस्लिम कांग्रेस से नाराज हैं। राजीव ने इधर कभी भाजपा या आरएसएस की आलोचना नहीं की है। लिहाजा, कोई आश्चर्य नहीं कि 'हिंदू-सेंटीमेंट' के तहत ही राजीव गांधी आदिवासी मतों को बटोरने की नीति अपनाये हुए हों। शायद राजीव गांधी यह समझते हों कि यदि जंगल की यह भूखी-नंगी फौज उनके पीछे लग गयी, तो कांग्रेस का सबसे जबर्दस्त लड़ाकू कैडर

कब आयेगा मीमादेव (पानी का देवता) ? : बूंद-बूंद के लिए तरसती आदिवासी औरतें

उनके लिए तैयार हो जायेगा। राजीव गांधी को शायद इस बात का पूरा अहसास है कि उनके नाना पंडित नेहरू और मां श्रीमती गांधी के लंबे शासन में ही ये आदिवासी टूटे हैं।

आजादी के बाद शोषण व दमन के चरमोत्कर्ष से जूझते-टूटते दलित-हरिजनों ने कभी अलग प्रांत की मांग इसलिए नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में तमाम उपेक्षा के बावजूद हरिजनों की एक पहचान कायम कर दी गयी है। पर आदिवासियों की ऐसी कोई पहचान राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर कभी नहीं बनी और इसका एक अहम कारण यह भी था कि दलितों व हरिजनों के वास्ते गांधी या अंबेदकर सरीखे नेता कारगर पहल कर गये, पर आजादी के बाद या पहले गांधी या अंबेदकर सरीखा नेता आदिवासियों को नसीब नहीं हुआ। गांधी हरिजन नहीं थे, पर हरिजनों के लिए विह्वल थे, इसलिए भी आजादी के कई दशक बाद तक भी हरिजन अपना नेतृत्व किसी गैरहरिजन के हाथों सौंपने में ज्यादा सोच-विचार नहीं करते थे। यहीं वजह है कि नक्सली हो रहे हरिजनों का नेतृत्व गैरहरिजन नक्सली नेता विनोद मिश्र या नाग भूषण पटनायक जैसे लोगों को मिला है। क्योंकि आजादी के न तो पहले न ही बाद में किसी गैरआदिवासी नेता या राजनीतिक दल ने आदिवासियों की तड़प को भांपने की जहमत उठायी, इसलिए आम आदिवासियों के मन में संभवत: यह धारणा हरदम के लिए घर कर गयी कि अपनी लड़ाई के लिए उन्हें अपना दल व अपना नेता खुद गढ़ना होगा। उनके लिए कोई गांधी या विनोबा नहीं आनेवाला, इसलिए इधर के दिनों में जब कभी किसी गैरआदिवासी नेता ने आदिवासियों के सवाल पर जेहाद छेड़ने की डुगडुगी बजायी, तो आदिवासी उत्साहित होकर भागते हुए उसके पीछे नहीं पहुंचे, बल्कि बारबार उन्हें लगा कि यह गैरआदिवासी नेता जरूर उनके संग फिर कोई नयी चाल खेलने आया है।

केवल छलावा : पंडित नेहरू ने अपने प्रधान मंत्रित्व काल में महज ऊपरी तौर पर ही आदिवासियों के लिए बातें कीं। १९५२ में दिल्ली में आयोजित 'अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय सम्मेलन' के एक अधिवेशन में पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा था—भारत के आदिवासियों में बड़ी शक्ति है और वे स्वभावतः कभी-कभी सही रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर भी चलने लगे। उन्होंने आपस में लड़ाई-झगड़ा किया और एक दूसरे का गला काट डाला। ऐसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं और इन्हें रोकना ही चाहिए।" लेकिन पंडित नेहरू ने भी कभी इस बात पर ज्यादा गौर करने की तकलीफ नहीं की कि आखिर वे कौन सी वजहें हैं, जो आदिवासियों को एक दूसरे का सिर उतार लेने की सीमा तक हिंसक कर देती हैं। अपने ही स्वजनों के प्रति अगर आदिवासियों में हिंसक मनोवृत्ति रही है, तो क्या उसके पीछे भूख व पिछड़ापन का कारण तो नहीं था, जिसे दूर करने की हलकी-सी पेशकश की जाती

श्रीमती गांधी का भी रुख आदिवासियों के वास्ते बहुत हार्दिक नहीं था। इसलिए देश में जब कभी हरिजन या मुसलमान मारे गये तो वह सत्ता में रहते हुए या सत्ताविहीन होते हुए भी उन जगहों पर भागी हुई पहुंचीं। पर जहां आदिवासी जुल्म व पुलिस दमन के शिकार हुए, तो श्रीमती गांधी ने भी उन्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं समझी। आदिवासियों के प्रति उदासीनता का रोष सिर्फ पंडित नेहरू या श्रीमती गांधी में ही नहीं था, बल्कि देश में विपक्षी राजनीति के जितने भी रहनुमा हुए सबके सब आदिवासियों के प्रति उदासीनता का भाव रखते रहे। चाहे लोहिया या जेपी ही क्यों न हों—इन विपक्षी विभूतियों ने भी कभी जंगल के दर्द को स्वर नहीं दिया। कारण शायद एक ही था कि आजादी के बाद दशकों तक आदिवासियों का राजनीतिक महत्व नहीं समझा गया।

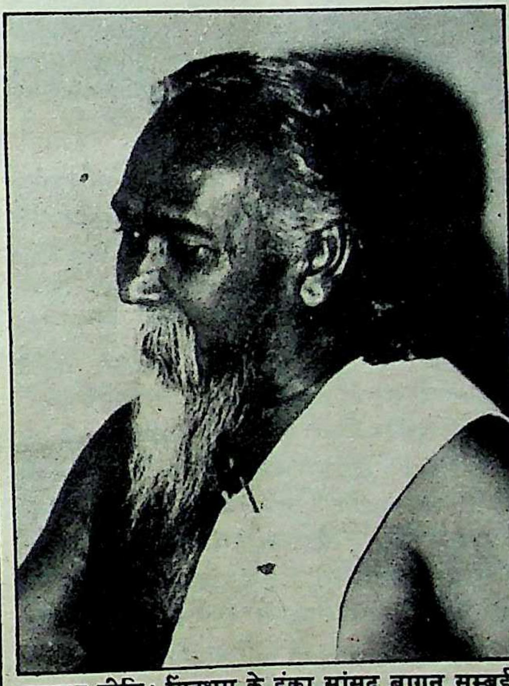

ढुलमुल नीति : सिंहभूम के इंका सांसद बागुन सुम्ब्रई

असम को बंटने नहीं देंगे : मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत

देश की राजनीति में आदिवासियों की स्थिति बस चिड़ियाघर के वन्यजीवों की-सी होकर रह गयी। पर बाद के दिनों में विपन्न आदिवासियों को अपनी राजनीतिक-दरिद्रता के बेचैनी से आभास हुआ। फिर तो बिहार के भी छोटानागपुर सिंहभूमि आदि इलाके में झारखंड पार्टी, हुल झारखंड सरीखे अनगिनत दल बनने शुरू हो गये। इन आदिवासी संगठनों ने बहुत थोड़े समय में गहरा प्रभाव कायम भी किया। कारगर राजनीतिक नेतृत्व के अभाव के कारण आदिवासी कांग्रेस के साथ आधे मन से विवशता में रहते आये थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए आदिवासी अंचलों में कांग्रेस से सीधी टक्कर लेने के लिए जब आदिवासियों ने अपना लड़ाकू आदिवासी नेता व संगठन खड़ा करना शुरू किया, तो कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़नी शुरू हो गयी। शिक्षा से कोसों दूर, आर्थिक पिछड़ेपन से टूटे आदिवासियों के अवचेतन में गजब की राजनीतिक चेतना शायद तहदर्ज होकर पड़ी थी जो एकबारगी कई प्रांतों में बेसाख्ता फूट पड़ी। कांग्रेस के खिलाफ जिस आदिवासी कार्यकर्ता में आदिवासी समाज ने चिनगारी देखी बस फौरन उसे समर्थन देकर रातोरात अपना नेता बना दिया। इसलिए दक्षिण बिहार में जयपाल सिंह सरीखे आदिवासी नेता जब कांग्रेस विरोधी परचम लहराते हुए उठे, तो आदिवासियों ने उन्हें हाथो-हाथ लिया और उनकी झारखंड पार्टी को विधानसभाई चुनाव में प्रबल समर्थन दिया। इसी तरह बिहार के आदिवासी क्षेत्र में बागुन सुम्ब्रई ने शुरू में कांग्रेस से अपनी घृणा जाहिर की, तो उनके द्वारा उन दिनों गठित झारखंड पार्टी को भी आदिवासियों ने चुनाव में जोरदार समर्थन दिया और इधर हाल के वर्षों में जब शीबू सोरेन बिहार के संथाल परगना के इलाके में कांग्रेस विरोध की मुनादी करते हुए राजनीतिक रंगमंच पर अपनी पार्टी 'झारखंड मुक्तिमोर्चा' लेकर अवतरित हुए, तो आदिवासियों ने उन्हें एक बार वोट देकर संसद में भेज दिया। शीबू राष्ट्रीय स्तर पर इसके बावजूद अपनी पहचान नहीं बना सके। बाद में विधानसभाई चुनाव में शीबू सहित झारखंड मुक्तिमोर्चा के अन्य उम्मीदवारों को आदिवासियों ने विजय का पारंपरिक आदिवासी साफा बांधकर बिहार विधानसभा में इस उम्मीद के साथ बिठाया कि मोर्चा के ये विधायक विधानसभा में कांग्रेस से मोर्चा लेंगे। पर कांग्रेस से नाराज आदिवासियों का यह दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस के खिलाफ जिताकर उन्होंने अब तक अपने जितने आदिवासी नेताओं को ससद या विधानसभा में भेजा, सबके-सब थोड़े ही दिनों बाद कांग्रेस में जा मिले। बिहार में स्व० जयपाल सिंह, बागुन सुम्ब्रई जैसे नेता तो साफ कांग्रेस के पालने में सो गये और बाद में शीबू सोरेन ने भी कांग्रेस के साथ परोक्ष रूप से दोस्ती गांठ ली। हर चुनाव में बजाय विपक्ष से तालमेल करने के शीबू कांग्रेस से गंठबंधन करने लगे। नतीजतन, आदिवासियों के संग लगातर यह विवश परिस्थिति समाने आती रही कि कांग्रेस से ऐन वक्त में जा

आदिवासी औरतें आज भी असुरक्षित : प्रोमिला रानी ब्रह्मा

मिलते आदिवासी नेताओं को चुनाव में वोट दिया जाये। जिस तरह से अब तक आधे मन से कांग्रेस टिकट पर खड़े आदिवासी नेता को वे वोट देते आये, उसी तरह धोखा करके गये अपने लड़ाकू नेता को भी वोट दिया। पर यह विवशता क्षणिक रही और धोखा खाकर आदिवासियों ने फिर नये लड़ाकू संगठन को जन्म दिया, जो जंगल व पहाड़ की नेतागिरी में कांग्रेस से लोहा ले सके। तमाम दुरावस्था व आक्रोश के बाद भी आदिवासी नक्सली नहीं बने। नक्सलियों ने भी पाया कि आदिवासियों में नक्सली नेतृत्व के प्रति आकर्षण नहीं है। हालांकि आंध्रप्रदेश व अब बिहार के भी कुछ हिस्सों में नक्सली आदिवासियों के बीच पांव रखने की जमीन बेसब्री से तलाश रहे हैं। नक्सलियों के प्रति आदिवासियों की लंबे अंतराल तक विमुखता के शायद दो प्रमुख कारण थे। एक तो उन्हें गैरआदिवासी नेतृत्व पर भरोसा नहीं था और दूसरे उनके अवचेतन में यह बात साफ थी कि नक्सली बनकर उग्रवादी गतिविधियों में मसरूफ होने के बजाय कुछ हासिल करने की राजनीति की मुख्यधारा में आने का उनका प्रयास निरर्थक हो जायेगा।

आदिवासी राजनीति के एक गहन विश्लेषक का मत है कि कांग्रेस के प्रति अरुचि रखते हुए भी आदिवासियों ने कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे आदिवासी नेताओं को भी इसलिए सींचा, ताकि सत्ता एकदम उनसे बिदक न जाये। पर वहीं कांग्रेस पर अरसे से स्थायी संदेह के कारण कांग्रेस पर कड़ा दबाव रखने की जरूरत की समझ के तहत घोर कांग्रेसी विरोधी आदिवासी राजनीतिक संगठन के अस्तित्व के प्रति निरंतर गहरी चिंता भी बरकरार रखी।

हरिजन सदैव सत्ता के साथ रहे। मुसलमान भी कभी कभार ही सत्ता विरोधी हुए। पर

मौजूदा सरकार से क्षुब्ध : एबीएसयू के अध्यक्ष उपेंद्रनाथ ब्रह्मा

आदिवासी कभी पूरी तरह सत्ता के प्रति समर्पित नहीं रहे। सत्ता का साथ दिया भी, तो सत्ता विरोधी अपने आदिवासी संगठन के वजूद पर खतरा मोल लेकर नहीं। यही वजह हुई कि बार-बार स्वतंत्र राजनीतिक दल की चाहत रखकर भी हरिजन कामयाब नहीं हुए और डा० अंबेदकर सरीखे व्यक्तित्वों को भी इस प्रयास में निराशा हाथ लगी। पर यह आदिवासियों का ही माद्दा था कि अरसे तक राजनीतिक पिछड़ेपन की नियति झेलने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ लड़ाकर अपने प्रतिनिधियों को देश की संसद या विधानसभाओं में बिठाकर दिखा दिया। पर राजनीति में इस तमाम गुरिल्ला-युद्ध के बावजूद आदिवासियों ने आखिरकार पाया कि उनके हिस्से तो कुछ भी नहीं आया। बिहार में आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सूरज सिंह बेसरा या फिर असम में आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सरीखे युवा नेतृत्व अलबत्ता जरूर उभर कर आये, पर राजनीति की राष्ट्रीय धारा में आदिवासियों की डेंगी उतारकर खेने वाले नेता की मुहताजी आज भी है। ऐसे में राजीव गांधी की मुहिम पर आदिवासियों की नयी पीढ़ी की नजर जा रही है। हालांकि राजीव जिस किसी आदिवासी क्षेत्र की यात्रा में जो वायदे कर आये, वे आज तक पूरे नहीं हुए। पर आदिवासियों का कुछ पढ़ा-लिखा नया तबका यह तर्क दे रहा है कि आखिर राजीव उनके गांवों में आये तो सही। अभी मई के अंतिम सप्ताह में राजीव गांधी दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर आये और मुंडा बस्ती में खुद कार चलाकर गये। राजीव देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मुंडा बहुल इलाके के गांवों में गये थे। घाटशिला की सभा में राजीव ने आदिवासी 'सेंटीमेंट' को अपनी तरफ करने में यह कहकर कारगर कोशिश की कि आदिवासियों की मानकी-मुंडा व्यवस्था सरकार बहाल रखेगी और आदिवासी समाज के

कोकराझाड़ की जिम्मेदारी : असम के राजस्वमंत्री थानेश्वर बोरो

सभी आंतरिक कानूनों को बरकरार रखा जायेगा। हालांकि राजीव की रांची यात्रा में 'आजसू' ने झारखंड-बंद का आह्वान किया था, पर आदिवासी इसके बावजूद बेहद उत्साहित थे। पूरे कार्यक्रम में राजीव आदिवासियों का पारंपरिक साफा बांधे रहे। सवाल फिर वही उठता है कि क्या राजीव अपनी इस मुहिम में कामयाब हो पायेंगे? क्या राजीव गांधी राजस्थान के आदिवासियों के लिए 'कालूराना', मध्यप्रदेश के आदिवासियों के लिए 'भीमादेव' तथा मुंडा आदिवासियों के लिए 'मारंगबोंगा' सिद्ध हो सकेंगे।

राजीव ने रांची में ईसाई मिशनरीवालों से भी मुलाकात की। रांची राजभवन में रोमन कैथोलिक मिशन के आर्क बिशप और चर्चेज ऑफ नार्दन इंडिया के बिशप से भी मशविरा किया। राजीव-राज में यों भी सोनिया गांधी के कारण ईसाई-लॉबी ताकतवर हुई है। सो राजीव संभवतः इस मसले पर आश्वस्त हैं कि ईसाई मिशनरी उनका साथ देगी। परोक्ष रूप से ईसाई मिशनरियां आदिवासियों के बीच कांग्रेस का ही काम कर रही हैं। इतना तय है कि ईसाई मिशनरियां लोकदल, जनतापार्टी, या कम्युनिस्टों का साथ कभी नहीं देंगी। भाजपा जहां चप्पे-चप्पे में ईसाई मिशनरियों की मुखालफत में जुटी है, वहीं कांग्रेस सदैव मिशनरियों का साथ देती रही है। यह भी शायद एक वजह है कि कांग्रेस पर तमाम गुस्से के बावजूद आदिवासियों ने कांग्रेस को एकदम से नहीं नकारा।

राजीव की रांची यात्रा में पारंपरिक रूप से आदिवासियों ने राजीव के हाथ-पांव पखारे और गीत गाये कि हमारे पास फूलों के सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर राजनीतिक पंडित समझ रहे हैं कि देश के आदिवासी अंचलों में राजीव सिर्फ फूल बटोरने के लिए नहीं घूम रहे हैं।

—विकास कुमार झा

विवादों में बनी रहने का चस्का : चंद्रिका केनिया

चंद्रिका केनिया

फिर नये 'ट्रस्टों' का तूफान

इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान को लेकर अब्दुल रहमान अंतुले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार की कानून और शिक्षामंत्री चंद्रिका केनियां अपने ट्रस्ट 'हम लोग फाउंडेशन' की वजह से विवादों में घिर गयी हैं। उनके ऊपर लाखों रुपए बतौर सूद के उगाहने के आरोप हैं। इससे जहां उनके विरोधी मुरली देवड़ा पार्टी के अंदर हलचल मचाने में सफल-हुए हैं, वहीं भाजपाई विधायक रामदास नायक अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। ट्रस्टों का यह नया तूफान मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण के लिए किस कदर गले की फांस बन गया है?

"इक जरा-सी बात में, सालों के याराने गये।
फिर भी इतना हुआ कि लोग पहचाने गये।।"

'लफड़ा मंत्री' के नाम से विख्यात महाराष्ट्र की शिक्षा एवं कानून राज्यमंत्री (कु०) चंद्रिका केनिया ने उक्त इबारत को जब अपने नवगठित 'हम लोग फाउंडेशन' के वार्षिक पुरस्कार समारोह स्मारिका में छपने के लिए चुना था, तो उन्हें पता नहीं था कि अनजाने ही वह एक कड़वे सच का साक्षात्कार करने जा रही हैं। उनके तीनों ट्रस्टों (हम लोग फाउंडेशन, आल इंडिया इंदिरा गांधी महिला फेडरेशन तथा प्रियदर्शिनी ट्रस्ट) के औचित्य को लेकर न केवल महाराष्ट्र की स्थिर हो रही राजनीति के तालाब में तूफान आ जायेगा, बल्कि जिस शख्स के साथ उनकी वर्षों की दोस्ती थी, जो अपने को उनका गुरु, दोस्त और मार्गदर्शक मानता था, वही उनका कट्टर दुश्मन हो जायेगा और उन्हें उस कांग्रेस पार्टी से निकालने की मुहिम शुरू कर देगा, जिसमें लगभग पौन दशक पहले राजनीति की दीक्षा देकर प्रवेश दिलवाया था।

बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा सांसद मुरली देवड़ा ने विपक्ष की राजनीति में बड़ी तेजी से उभर रही तथा उमरखाड़ी क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही चंद्रिका केनिया को लाकर कांग्रेस में प्रतिष्ठित कराया था और मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें मुरली देवड़ा के उस गुट से तोड़ लिया था, जो भीतर-ही-भीतर, लेकिन अप्रकट रूप से, उनकी सत्ता की नींव पर प्रहार करने में जुटा हुआ था। हर समय मुस्करा कर मीठे स्वर में बात करनेवाले सांसद मुरली देवड़ा अपनी शिष्या की बेवफाई पर तब कसमसा कर रह गये थे, जब उन्हें केनिया की मुख्यमंत्री के पुत्र अशोक चह्वाण के साथ बढ़ती दोस्ती का पता चला। तभी से बदले के लिए मौके की तलाश में लगे देवड़ा को उस समय उपयुक्त मौका मिल गया, जब उन्हें केनिया द्वारा गठित तीनों प्रतिष्ठानों के बारे में पता लगा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली-बंबई संपर्क को तीव्र कर दिया, लेकिन प्रकटतः अपने को शांत ही व्यक्त किया।

ट्रस्ट या मुसीबत ; महाराष्ट्र की राजनीति का यह दुर्भाग्य ही है कि जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री फाउंडेशन या ट्रस्टों की स्थापना शुरू करता है, तो वह मुसीबत में फंस जाता है। वसंत राव नाईक, वसंत दादा पाटील, अब्दुल रहमान अंतुले जैसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों तथा रजनी पटेल, रामराव आदिक, शालिनी ताई पाटील जैसे चाणक्य-राजनीतिज्ञों का सूर्यास्त और पराभव इन्हीं ट्रस्टों के कारण हुआ। यों देश में राजनीतिज्ञों द्वारा गठित सर्वाधिक ट्रस्ट एवं फाउंडेशन महाराष्ट्र में ही हैं, जहां अधिकांश उच्च शैक्षणिक संस्थान सांस्कृतिक संगठन तथा सहकारी प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाता कुशल राजनीतिज्ञ ही हैं, जिन्होंने अपने प्रभाव और पद का उपयोग कर पानी के मूल्य जमीनें तथा विवादास्पद भूखंडों पर अपने ट्रस्ट का कब्जा दिला दिया।

मुरली देवड़ा-केनिया के बीच विवाद पिछले वर्ष विलेपार्ले में हुए विधानसभाई उपचुनाव के समय उभर कर सामने आ गया, जब कांग्रेसी उम्मीदवार प्रभाकर कुंठे को शिवसेना के मुकाबले पराजय का सामना करना पड़ा। २६ मई '८८ को जब नयी कांग्रेस महासचिव तथा महाराष्ट्र की प्रभारी श्रीमती शीला कौल महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक मतभेद को सुलझाने के लिए बंबई आयीं, तो चंद्रिका केनिया ने देवड़ा ऐंड कंपनी (जिसमें वसंत दादा पाटील, शरद पवार [illegible] नेता भी हैं) पर खुला आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझ कर कांग्रेसी उम्मीदवार प्रभाकर कुंठे को हराने की साजिश शिवसेना के साथ मिल कर रची थी।

समारोह का बहिष्कार : चंद्रिका केनिया की बौखलाहट संभवतः सीमा पार नहीं करती, अगर प्रतिपक्षी कांग्रेसी गुट उनके तीनों प्रतिष्ठानों तथा २६ मई को हुए इंदिरा गांधी एवार्ड समारोह को असफल बनाने के लिए खुलकर सामने नहीं आ जाता। चंद्रिका केनिया ने इस पुरस्कार समारोह को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और उसे सफल बनाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही थीं। दूसरी तरफ, उनका विरोधी गुट पुरस्कार के लिए नामजद व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें समारोह में शामिल न होने के लिए प्रेरित कर रहा था। फलतः मदर टेरेसा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रतापराव राणे, महासचिव गुलाम नबी आजाद, वसंत दादा पाटील, धीरूभाई अंबानी, राहुल बजाज तथा श्रीदेवी ने पुरस्कार ग्रहण करने या समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। केनिया के इस समारोह के विरुद्ध प्रचारात्मक पोस्टर सारे महानगर में चिपकाये गये, इसके बाद दोनों पक्षों का पोस्टर तथा अपील युद्ध शुरू हो गया।

१८ मई '८८ को केनिया द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन में 'हम लोग फाउंडेशन' के तत्वावधान में पुरस्कार के लिए नामजद राजनीतिज्ञों, फिल्म कलाकारों, पत्रकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची घोषित की, तो दूसरे ही दिन मुरली देवड़ा के प्रबल समर्थक-पार्षद कांति धुल्ला ने केनिया के तीनों ट्रस्टों की वैधता को चुनौती देते हुए उनकी पुलिस से जांच कराने की मांग की तथा ट्रस्टों की तुलना अंतुले के उस विवादास्पद इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान से की, जिसमें भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के कारण उन्हें

साक्षात्कार/चंद्रिका केनिया

हम इतने बेवकूफ नहीं कि आंख मूंदकर गलत ट्रस्ट बना दें

मासूम भोला चेहरा, बातचीत में बेबाकी तथा अपरिचितों के सामने बड़ी जल्दी खुलकर बोलने में न हिचकने वाली तथा उतनी ही जल्दी तैश में आकर आपा खो बैठनेवाली चंद्रिका केनिया क्रिकेट की दुनिया से राजनीति के चक्रव्यूहों-भरे संसार में, अपनी विशिष्ट शख्सीयत के बल पर, बड़ी जल्दी फिट हो गयीं। उमरखाड़ी से महानगरपालिका के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर खड़ी केनिया जब अपनी चुनाव सभाओं में स्व० प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस पर दो-टूक हमला करती थीं, तो सुनने और देखनेवाले हैरान रह जाते थे। 'उमरखाड़ी की लक्ष्मीबाई' के नाम से विख्यात केनिया जब मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण के मंत्रिमंडल में १९८६ में शामिल हुईं, तो किसी को आभास भी नहीं हुआ था कि अपने बेबाक व्यवहारों से वह सर्वाधिक विवाद का केंद्र बन जायेंगी। अपनी तेज-तर्रार शख्सीयत तथा बड़बोलेपन के कारण उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी तथा महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया। बंबई-पुणे विमान यात्रा के दौरान विमान परिचारिका को डांट पिला कर जहां विमान कर्मचारियों की हड़ताल का खतरा पैदा कर दिया, वहीं पुणे की एक छात्रा को सरेआम झापड़ मार कर खुद के लिए संकट मोल ले लिया तथा विधानसभा अधिवेशन के दौरान अपने सचिव को कार्यवाही कक्ष के भीतर बुलाकर समूची विधानसभा के रोष का भाजन बन गयीं। इधर अपने ट्रस्टों के कारण वह विवाद के घेरे में आ गयी हैं। 'माया' ने उसी विवाद के संबंध में उनसे बातें कीं। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

माया: कुछ लोग आपको लफड़ा मंत्री, तो कुछ लोग आग उगलनेवाली मंत्री कहते हैं?

केनिया: लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, मैं फालतू की बातों में विश्वास नहीं करती, सिर्फ अपने काम में विश्वास करती हूं।

माया: आपने अभी कुछ दिनों पहले बंबई कांग्रेस कमेटी को 'तस्करों-गुंडों का अड्डा' कहा था?

केनिया: मेरे कथन को थोड़ा मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे कहने का आशय था कि कमेटी के कुछ अधिकारी गलत हैं। वे लोग शिवसेना के इशारों पर काम करते हैं।

माया: आपने दो मंत्रियों (वी सुब्रह्मण्यम तथा विलास सावंत) तथा सांसद मुरली देवड़ा पर भी आरोप लगाये थे।

केनिया: अब छोड़िए इसे। विवाद बढ़ाने से क्या फायदा?

माया: लेकिन इन लोगों ने आपको पार्टी से निकालने की मांग की है और आपको निकालने पर पूरी तरह से तुल गये हैं।

केनिया: पार्टी किसी की प्रापर्टी नहीं है कि जिसे चाहा उसे निकाल दिया। मैं गलत होऊंगी, तभी तो मुझे निकाला जायेगा और वह संभव नहीं।

माया: आप अपने पूर्व बयान से मुकर क्यों गयी थीं? क्या मुख्यमंत्रीजी के दबाव से ऐसा किया था?

केनिया: मैं मुकरी नहीं थी, सिर्फ स्पष्टीकरण दिया था और स्पष्टीकरण करना गलत तो नहीं?

माया: आपने तीन ट्रस्ट बना रखे हैं, लोगों का आरोप है कि ये पंजीकृत नहीं हैं—गैरकानूनी हैं, अंतुले के इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान की तरह।

केनिया: नहीं, ये बाकायदे रजिस्टर्ड हैं। आप चाहें, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखला सकती हूं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि बिना कानूनी मुद्दों, सरकारी नियमों-प्रावधानों का अध्ययन किये आंख-मूंदकर गलत ट्रस्ट या फाउंडेशन बना दें। हम यह काम समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, निजी फायदे के लिए नहीं।

माया: श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम का बिना मंजूरी लिये अंतुले ने उपयोग किया था, तो वह संकट में फंस गये थे। क्या आपने आलाकमान से मंजूरी ली थी?

केनिया: हां।

माया: इसके लिए आप दिल्ली गयी होंगी, वहां जरूर आपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी मुलाकात की होगी। क्या बात हुई थी, आप दोनों के बीच?

केनिया: (मुसकरा कर) नो कमेंट!

माया: आपके विरोधियों का कहना था कि आपने बिना रसीद के लाखों रुपए बतौर चंदे उगाहे थे।

केनिया: उन्होंने आपको उन लोगों के नाम भी बतलाये होंगे, जिनसे ये रुपए उगाहे गये होंगे। क्यों नहीं आप उन लोगों से मिलकर सचाई का पता लगा लेते हैं।

माया: अच्छा, रसीद देकर ही सही-कितने रुपए आपने एकत्र किया है ट्रस्ट के लिए?

केनिया: सिर्फ स्मारिका से एक लाख रुपए विज्ञापन के रूप में एकत्र हुए थे। ये रुपए सूखा राहत कोष के लिए दे दिये जायेंगे।

माया: कांति धुल्ला ने आरोप लगाया है कि तीनों ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन में आपने अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

केनिया: गलत आरोप है। आप रजिस्ट्रेशन करने वाले कार्यालय में जाकर पता लगा लें।

माया: प्रतिष्ठानों के नाम के साथ इंदिरा गांधी का नाम जोड़ने से क्या 'नेम्स ऐंड एंबलम कानून' की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं होता?

केनिया: नहीं किसी भी धारा का नहीं। सभी कुछ वैधानिक ढंग से और विधिवत हुआ है।

माया: अभी पिछले दिनों जिस तरह से आपकी नीयत पर शक किया गया और आपके विरुद्ध विवाद खड़े किये गये, उसे आप क्या कहेंगी?

केनिया: मेरे ऊपर प्रहार करने का मतलब सीधे महाराष्ट्र सरकार पर प्रहार करने के समान है। सीधे मुख्यमंत्री को धर्मसंकट में डालने का प्रयास है।

माया: आपके एक पड़ोसी (वसंत दादा पाटील) मुख्यमंत्री चह्वाण को हटाने पर तुले हुए हैं, दूसरे पड़ोसी (शरद पवार) उनकी कुरसी पर खुद बैठना चाहते हैं। आपकी क्या राय है, इस बारे में?

केनिया: नो कमेंट!

माया: और मुरली देवड़ा के बारे में?

केनिया: नो कमेंट प्लीज!

—रजनीकांत

सत्ताच्युत होना पड़ा था। कांति धुल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि ये तीनों ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर कार्यालय से बाकायदा पंजीकृत नहीं किये गये हैं, ये केनिया के निजी ट्रस्ट हैं और इनसे 'नेम्स ऐंड एंबलम ऐक्ट' का खुला उल्लंघन हुआ है। केनिया ने इन ट्रस्टों के नाम पर उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों से लाखों रुपए बतौर चंदा उगाहे हैं।

इससे बौखलायी केनिया ने २५ मई '८८ को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित कर बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अधिकांश पदाधिकारियों को गुंडे, ब्लैकमेलर तथा तस्कर की उपाधि दी और कांति धुल्ला को झूठा, फरेबी तथा ब्लैक मेलर की संज्ञा देते हुए कहा, "कांति धुल्ला एक दूसरे पार्षद (उपेंद्र जोशी) के साथ मिलकर सागर फ्रेंड्स सर्किल तथा श्रद्धा पब्लिक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसके माध्यम से पैसे खाये गये, बिना रसीद के चंदा जमा किया गया। केनिया ने बंबई कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव शाहनवाज खान तथा एक तालुकाध्यक्ष मासूम भाई का नाम लेते हुए हुए कहा, "शाहनवाज खान के खिलाफ पुलिस में बलात्कार के मामले दर्ज हैं तथा मासूम भाई सोशल क्लब चलाते हैं और जाने-माने समाज विरोधी हैं।" उन्होंने मुरली देवड़ा को भी यह कहते हुए नहीं बख्शा कि 'देवड़ा साहब कहते हैं कि पार्टी को गुंडों की जरूरत है। उन्होंने (देवड़ा) क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी को तस्करों व असामाजिक तत्वों का अड्डा तथा 'चैंबर आफ कामर्स' बना रखा है, जहां दलाल और बिल्डर (भवन-निर्माता) सक्रिय रहते हैं, जिनका फायदा कांति धुल्ला जैसे लोग अपने लिए उठाते हैं। यहां का माहौल ऐसा हैं कि मेरी जैसी लड़की वहां पर जा ही नहीं सकती। कानून राज्यमंत्री की हैसियत से मैं इन ट्रस्टों की छानबीन करूंगी।' मजेदार बात यह थी कि उन्होंने प्रेस सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण द्वारा जारी किये गये इस वक्तव्य 'मुरली देवड़ा तथा चंद्रिका केनिया के बीच विवाद शीघ्र खतम हो जायेगा' के तुरंत बाद किया था।

धमाका : चंद्रिका केनिया के इस वक्तव्यं ने देवड़ा गुट पर धमाका-सा बरपा दिया। एक तरफ जहां कांति धुल्ला ने केनिया को अपने ऊपर लगाये गये गलत आरोपों को प्रमाणित करने या इस्तीफा देने की चुनौती, सागर फ्रेंड्स सर्किल तथा श्रद्धा पब्लिक ट्रस्ट से संबंधों का खंडन किया और केनिया को 'अरुण नेहरू का आदमी' बतला कर मुरली देवड़ा से केनिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, वहीं २६ मई को बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की महिला फ्रंट की कार्यकर्ताओं ने केनिया की अनुपस्थिति में, पुलिस द्वारा लाख रोकने के बावजदू, उनके बंगले में घुसकर तोड़-फोड़ तथा लूटपाट की। ड्राइंग रूम में केनिया के पोर्ट्रेट तथा सेंटर टेबुल का कांच व टेलीफोन के तार तोड़ने के बाद वे दीवाल पर टंगे राजीव गांधी के साथ केनिया के चित्र व राजीव गांधी के पोर्टेट भी तोड़ने के लिए बढ़ीं, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक कर राजीव गांधी के पोर्टेट की रक्षा कर ली। कुछ महिलाएं घरेलू सामान भी अपने साथ उठा ले गयीं। केनिया विरोधी नारे लगा रही महिला कार्यकर्ताएं तब तक वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थीं, जब तक केनिया वहां आ न जायें और वे रूबरू उन पर अपना विरोध प्रकट न कर दें। तभी महिला फ्रंट की एक दूत ने आकर उन्हें 'नेता' का संदेश देते हुए तुरंत बंगले के बाहर चले जाने का निर्देश दिया। चंद्रिका केनिया तथा उनके समर्थक इस 'नेता' का नाम मुरली देवड़ा बतलाते हैं, जिनके निर्देश पर महिला कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित ढंग से उनके बंगले पर हमला बोला था।

केनिया के जवाबी हमले का जवाब शाहनवाज खान ने उनके गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य के लिए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर तथा बंबई क्षेत्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश विनसाले ने केनिया को तुरंत पार्टी से बरखास्त करने व पुलिस से उनके अवैध ट्रस्टों की जांच की मांग कर दिया। बंबई कांगेस कमेटी के संयुक्त सचिव श्यामल दत्त गुप्त तथा अभी तक इसे 'कांग्रेस का आंतरिक मामला मानकर चुप रहने वाले मुरली देवड़ा भी खुल गये और वह पत्र पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने मासूम भाई को तालुकाध्यक्ष बनाने का आग्रह कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया था। दक्षिण बंबई जिला युवक कांग्रेस कमेटी ने भी केनिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अपील की। दूसरी तरफ दक्षिण बबई जिला महिला कांग्रेस कमेटी व कांग्रेसी मजंदूर नेता गुलाब जोशी ने केनिया की कार्रवाई को सही ठहराते हुए मुरली देवड़ा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। महानगर के ११० वकीलों ने एक ज्ञापन जारी कर केनिया के 'हम लोग फाउंडेशन' की तारीफ करते हुए कहा कि इसका गठन खेल-कूद, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं करनेवाले लोगों को सम्मानित करने तथा युवा वर्ग को सुनहरे अवसर उपलब्ध करा कर राष्ट्र निर्माण का स्वप्न साकार करने के लिए किया गया है। इसे राजनीतिक विवाद का रूप ही देना गलत है। चंद्रिका केनिया पुरस्कार वितरण समारोह को असफल बनाने की तथाकथित मुहिम के विरुद्ध हर संघर्ष करने के लिए तैयार थीं। उनका कहना था कि 'लोग समारोह में आयें चाहे न आयें, लेकिन समारोह होकर ही रहेगा।' और २६ मई को उन्होंने समूचे विरोध के बावजूद पुलिस के कड़ें पहरे में पुरस्कार वितरण का कमाल कर दिखलाया। समारोह की तिथि से एक दिन पहले तक समारोह की सदारत करने की अपनी जिद्द पर अड़े मुख्यमंत्री ने २६ मई को अंततः अपना फैसला श्रीमती शीला कौल तथा वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह पर बदल दिया, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में आवास राज्य मंत्री सैयद अहमद को भेज दिया। पुरस्कार के लिए घोषित व्यक्तियों में फिल्म अभिनेता अशोक कुमार, विश्वविख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा० बीएम पुरंदरे, मराठी पत्रकार नीलकंठ खाडिलकर (संपादक, 'नवा काल'), गुजराती पत्रकार रसिक लाल भूता (मालिक-संपादक, श्रीवर्षा आदि) आदि ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण पहले तो इस सारे कांड का बड़ी तटस्थता तथा खामोशी से जायजा लेते रहे, फिर ऊपरी तौर पर, २६ मई '८८ को केनिया की बयानबाजी पर नाराजगी व्यक्त की

विवादास्पद : केनिया के हाथों 'हमं लोग फाउंडेशन' पुरस्कार प्राप्त करते हुए अभिनेता अनिल कपूर

और उन्हें आगे कोई कदम न उठाने का निर्देश दिया। उनकी सलाह को मानकर केनिया ने न केवल अपने पूर्व बयान को यह कहकर बदल दिया कि 'बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी को मैंने तस्करों का अड्डा नहीं कहा और न ही महिला फ्रंट की कार्यकर्ताओं ने मेरे घर पर हमला किया था।' फिर उन्होंने दूसरा वक्तव्य जारी किया कि 'सरकार के कुछ लोगों के उकसाने पर मैंने बंबई कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध आग उगली।' केनिया ने 'माया' को बतलाया, "अखबारवालों ने मेरी टिप्पणी को गलत समझ लिया था। मेरे कहने का मतलब था, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके संबंध ऐसे लोगों के साथ हैं जो शिवसेना से मिलकर पार्टी की नींव खोखली कर रहे हैं।"

चह्वाण उवाच: केनिया की बयानबाजी तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जायेगी, के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री चह्वाण ने अपने तरीके से एक तरह से उनका बचाव ही किया—"मैं इस बारे में अभी विश्वसनीय जानकारियां एकत्र कर रहा हूं, इसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। यों किसी को भी-पार्टी के लोगों अथवा बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के बारे में इस तरह का प्रेस में वक्तव्य देना गलत है। उन्हें जो कहना हो, पार्टी के मंच पर आकर कहना चाहिए।" लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उन्होंने केनिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस बारे में सांसद मुरली देवड़ा भी मुख्यमंत्री की विचारधारा के ही समर्थक निकले। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। मुझे जो कुछ कहना है, पार्टी में ही कहूंगा। पार्टी की बात मैं बाहर या प्रेस में नहीं लाऊंगा।" और उन्होंने यही किया।

महाराष्ट्र पर्यवेक्षक श्रीमती शीला कौल के बंबई पहुंचते ही, २८ मई '८८ को, तीन सांसदों (मुरली देवड़ा, सुधा जोशी व अनूप शाह), महाराष्ट्र के दो मंत्रियों (डा० वी सुब्रह्मण्यम व विलास सावंत) तथा १६ विधायकों ने श्रीमती कौल को एक ज्ञापन देकर केनिया को पार्टी से बरखास्त करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया कि चंद्रिका केनिया घमंडी तथा चिड़चिड़े स्वभाव की हैं। अपनों से बड़ों का अपमान करती रहती हैं। अपने उलटे-सीधे आचरणों द्वारा पार्टी को हमेशा शर्मनाक स्थिति में डाल दिया करती हैं। एक जमाने में वह स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध गालियां बका करती थीं। आज उन्हीं के नाम पर फाउंडेशन और पुरस्कार शुरू कर दिया है। इस ज्ञापन से दो दिन पहले २६ मई '८८ को महाराष्ट्र के पांच विधायकों (सीडी उमाचेन, वीरेंद्र बक्षी, जनार्दन चांदूरकर, जावेद खान तथा रमेश दुबे) ने भी बाकायदे एक विज्ञप्ति जारी कर केनिया को पार्टी से निकालने की मांग की थी।

अपने विरोधियों की इस मुहिम के प्रतिकार स्वरूप चंद्रिका केनिया ने भी अपने समर्थकों के साथ श्रीमती शीला कौल से अलग से भेंट कर अपनी स्थिति प्रकट की और एक ज्ञापन देकर बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी में मौजूद असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जब श्रीमती कौल ने उनके ज्ञापन लेने से मना कर दिया, तो केनिया ने ३१ मई '८८ को, केंद्रीय इस्पात मंत्री माखन लाल फोतेदार से बंबई में मिलकर 'हम लोग फाउंडेशन'— विवाद के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की तथा मुरली देवड़ा तथा दूसरे लोगों द्वारा उनके ऊपर लगाये जा रहे 'कुत्सित' आरोपों की भी चर्चा की। फोतेदार ने केनिया से मिलते ही सवाल किया—"आपने पुरस्कार एवं फाउंडेशन के साथ इंदिराजी का नाम जोड़ने से पहले आलाकमान की इजाजत ली थी या नहीं?" तो केनिया ने उन्हें बतलाया, "पार्टी के कई जिम्मेदार नेताओं ने उन्हें मौखिक अनुमति दी थी।"

उठते सवाल: सवाल उठता है, क्या केनिया के तीनों फाउंडेशन अंतुले के इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की तरह भ्रष्टाचार के केंद्र बन गये थे और केनिया ने अपने पद और प्रभाव का उपयोग कर, अंतुले की ही तरह, उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों से लाखों रुपए चंदे के रूप में उगाहे, जिसे इस बार खुद पार्टी के लोगों (असंतुष्ट गुट) ने ऐन उस समय उजागर किया, जब उनकी (असंतुष्टों) महाराष्ट्र का नेतृत्व बदलने संबंधी मांग का जायजा लेने के लिए शीला कौल बंबई आनेवाली थीं? एक तटस्थ विधायक का कहना था, "यह सब जानबूझ कर किया गया था, ताकि मूल समस्या पर से पर्यवेक्षक का ध्यान हटाया जा सके। चह्वाण गुट के एक प्रभावशाली नेता तथा राज्य मंत्री ने 'माया' को बतलाया, "यह उनकी (चह्वाण विरोधियों) सुनियोजित योजना थी। केनिया के बहाने मुख्यमंत्री को भ्रष्ट और नालायक साबित करने की अन्यथा जब केनिया ने अपने ट्रस्टों की स्थापना की थी तब किसी ने उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठायी थी कि ये ट्रस्ट गलत हैं या केनिया अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं अथवा अंतुले के मार्ग परे चल रही हैं। यह सारा विवाद ठीक तब शुरू किया गया, जब महाराष्ट्र पर्यवेक्षक के बंबई आने की योजना घोषित हुई।

GENERAL SECRETARY ALL

अपना-अपना राग अलापते हुए : (बायें से) दादा पाटील, प्रभाराव, शीला कौल, देवड़ा तथा चह्वाण

श्रीमती शीला कौल की तीन दिन की अनवरत बैठकों, मुलाकातों का फल वही 'ढाक के तीन पात' सदृश निकला, जो इसके बंबई आनेवाले महाराष्ट्र के भूतपूर्व पर्यवेक्षकों की बंबई की राजनीतिक यात्रा के दौरान निकला था। चतुर राजनीतिज्ञ की तरह श्रीमती शीला कौल बंबई से रवाना होते समय बड़े भोले अंदाज में यह कह गयीं, "मुझसे तो किसी ने भी नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं की। हर एक ने शिव सेना के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, इसे रोकने की पूरी कोशिश की जायेगी।"

'माया' प्रतिनिधि ने 'हम लोग फाउंडेशन' के पंजीकरण के संबंध में चैरिटी आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया, तो पता चला कि वहां दिये गये आवेदन पत्र में केनिया के भाई उदय केनिया को एक विशेष पद दिया गया है। केनिया ट्रस्ट व फाउंडेशनों के पंजीकरण में अपने पद और प्रभाव के इस्तेमाल का विरोध करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ दो दिनों के भीतर ७ अप्रैल '८८ को पंजीकरण मिल गया था, जबकि नियमतः पंजीकरण की प्रक्रिया में ३० दिन लग जाते हैं, जिसकी सूचना बोर्ड पर लगायी जाती है। उस ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए दिये गये आवेदन पत्र का अनुमोदन खुद चंद्रिका केनिया ने किया था। इसके पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का सिर्फ २४ घंटे में पंजीकरण हो गया था।

कांग्रेस के इस आंतरिक संघर्ष का विपक्षी दल मजा ले रहे हैं और असंतुष्ट गुट ने विधानसभा के मानसून अधिवेशन में मुख्यमंत्री चह्वाण तथा उनके लेफ्टिनेंटों को मुसीबत में डालने के लिए फिर एक नये चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। अंतुले को उनके प्रतिष्ठान के लिए अदालत के कठघरे तक ले जानेवाले भाजपा विधायक रामदास नायक ने इन प्रतिष्ठानों के औचित्य को लेकर अदालत जाने की तैयारी शुरू कर दी है। —बंबई ब्यूरो

आई.डी.बी.आई.

पूँजी-निवेश जमा खाता योजना

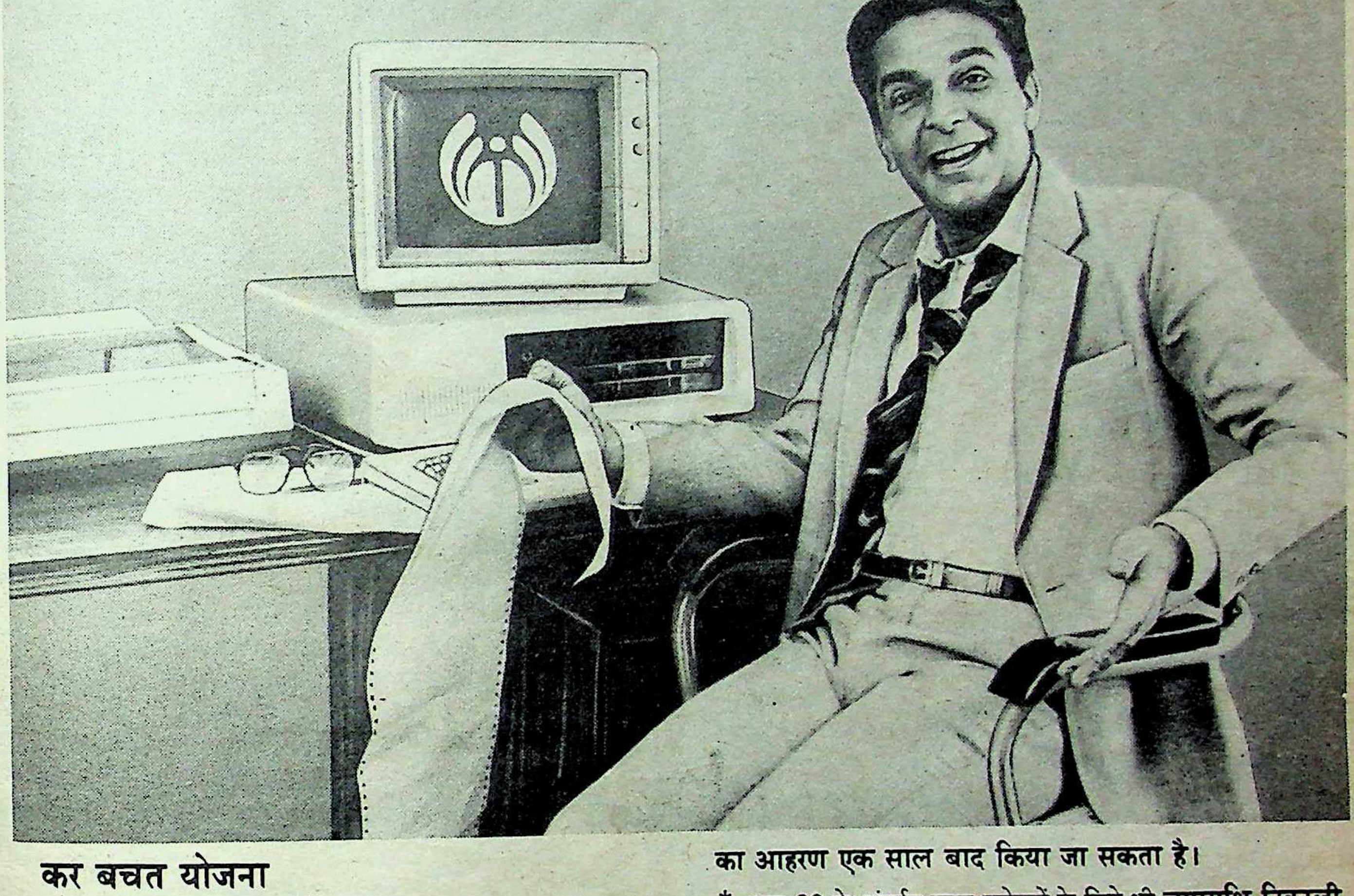

कर बचत योजना

उन सभी कंपनियों, व्यक्तियों, फ़र्मों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिये जिनकी आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 32 एबी के अंतर्गत **''व्यापार या व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियाँ''** शीर्षक के अधीन कर-योग्य है।

* **इस योजना के अंतर्गत जमाराशि करदाता की कर-योग्य आय के 20% तक कटौती की पात्र होगी।**

* **कर-बचत की पात्रता के लिये आवश्यक है कि कर-दाता लेखा-वर्ष की समाप्ति के 6 मास के अंदर या कर विवरण-पत्र (टैक्स रिटर्न) जमा करने के पूर्व** (जो भी पहले हो) निवेश-राशि जमा कर दे।

* जमा की गयी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। **आय-स्रोत पर कर-कटौती नहीं की जाएगी।** ब्याज की राशि किसी भी प्रकार के उपयोग के लिये मुक्त रूप से खाते से निकाली जा सकती है।

* कर-दाता के व्यापार या व्यवसाय से संबंधित संयंत्र, मशीन, कम्प्यूटर आदि को ख़रीदने या किसी अन्य मान्य प्रयोजन के लिये जमा **मूलधन का आहरण एक साल बाद किया जा सकता है।**

* धारा 32 के अंतर्गत मान्य प्रयोजनों के लिये भी **जमाराशि निकाली जा सकती है।** पूँजी-निवेश के लिये आवेदन पत्र डाक से भेजे जा सकते हैं। साथ में आई.डी.बी.आई. को देय बैंक ड्राफ़्ट या रेखित खाता अदायगी चेक भी होना चाहिए। बाहरी स्टेशनों के चेक भी स्वीकार किये जाते हैं। उनकी वसूली का व्यय आई.डी.बी.आई. द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक ड्राफ़्ट के मामले में ड्राफ़्ट ख़रीदने की तारीख़ ही निवेश जमा करने की तारीख़ मानी जाएगी, लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि ड्राफ़्ट की तारीख़ से 10 दिन की समुचित अवधि के अंदर ड्राफ़्ट आई.डी.बी.आई. को प्राप्त हो जाए। चेक जमा करने की तारीख़ ही आई.डी.बी.आई. द्वारा निवेश प्राप्त करने की तारीख़ मानी जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिये लिखें :– प्रबंधक,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) बम्बई 400 021 या आई.डी.बी.आई. के किसी भी कार्यालय से संपर्क करें। हर राज्य में आई.डी.बी.आई. का एक कार्यालय है)। अनुसूचित बैंकों के मुख्य कार्यालयों द्वारा अपनी सभी शाखाओं को पूरी जानकारी भेज दी गयी है।

Sobhagya-B/87 HN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
जॉली मेकर चैम्बर्स क्र. 2, 225, विनय के शाह मार्ग,
नरीमान प्वाइंट, बम्बई 400 021.

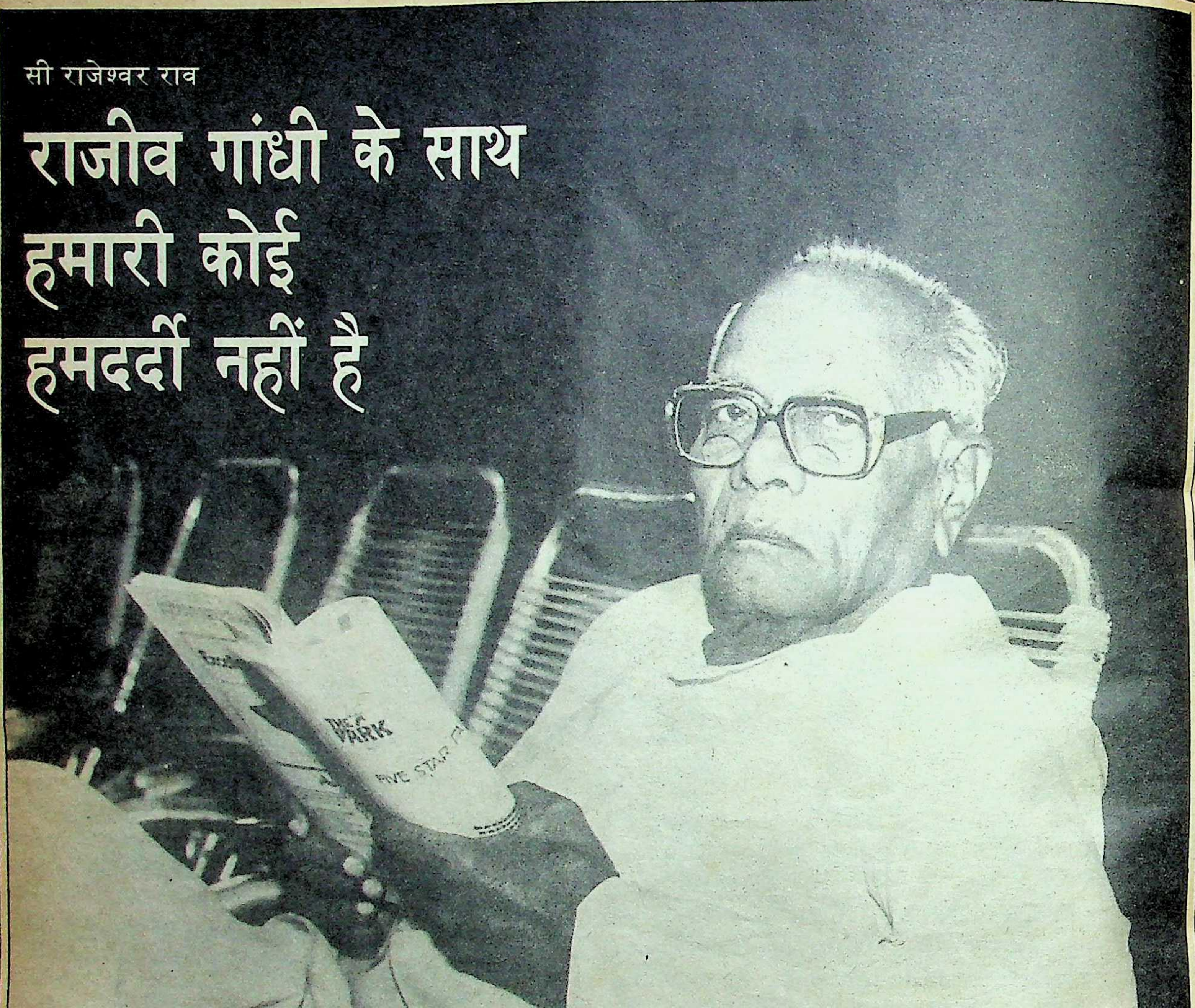

सी राजेश्वर राव

राजीव गांधी के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है

लंबे चौड़े कसरती बदन वाले चंद्र राजेश्वर राव को पहली नजर में देखने पर किसी किसान अथवा फौजी का भ्रम होता है। ७५ वर्षीय बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता की उपलब्धियों को देखते हुए यह एक अर्थ में सही भी है। खेती में उनकी खास दिलचस्पी है। १९३४ में कुलवक्ती कार्यकर्ता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने वाले कामरेड राव १९४३ से १९६१ तक के उस जुझारू दौर में पार्टी की आंध्र प्रदेश राज्य की समिति के सचिव थे, जब जमींदारों की भूमि पर कब्जे के लिए भूमिहीनों का ऐतिहासिक तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष चला था और जिसके अग्रिम लड़ाकू दस्ते के वह सेनानी थे। पार्टी विभाजन के बाद १९६४ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर संभालने वाले श्री राव के जीवन में तो कम, किंतु उनके कार्यकाल में पार्टी में बहुत उतार-चढ़ाव आया। इंदिरा गांधी की एक समय में डगमगाती नैया को पार लगाने वाली, इंका के साथ केरल में मार्क्सवादियों को धता बताकर साझा सरकार बनाने वाली, इमरजेंसी का समर्थन करने वाली और राजीव गांधी की सरकार को ललकारने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्षस्थ नेता के रूप में उनकी कुशलता, क्षमता, दूरदृष्टि और संगठन शक्ति इसी से उजागर है कि अनेक विपक्षी पार्टियां जहां सबसे ऊंची कुरसी की लड़ाई के लिए आपस में ही लहूलुहान हो रही हैं, वहीं कामरेडों के बीच सीआर के नाम से मशहूर राजेश्वर राव २५ वर्षों से निर्बाध निर्विवाद रूप में अपनी पार्टी को एकजुट-लामबंद किये हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की जानीमानी हस्ती और सोवियत संघ के सर्वोच्च लेनिन पुरस्कार से सम्मानित कामरेड राजेश्वर राव से 'माया' की ज्वलंत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों पर हुई विस्तृत बातचीत के प्रमुख अंश :

माया : *भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पहले से कितनी पास और कितनी दूर हैं?*

राजेश्वर राव : अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों पार्टियां काफी करीब हैं। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में विश्वशांति और महायुद्ध के बारे में जो मतभेद थे, अब नहीं रह गये हैं। इस अहम राष्ट्रीय मुद्दे पर भी सहमति है कि कांग्रेस सरकार को हटाकर एक वामपंथी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विकल्प बनाया जाये। सांप्रदायिक पार्टियों के विषय में भी दोनों पार्टियों की राय एक है। दोनों ही सांप्रदायिक पार्टियों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहतीं।

माया : *जब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद नहीं हैं, तो आप अलग-अलग क्यों हैं? क्या विलय की संभावना है?*

राव : अब हम समझते हैं कि वह संभावना नहीं है, क्योंकि पार्टी विभाजन १९६४ में हुआ था। २४ वर्ष हो गये। अतीत के जो मुद्दे थे, उन पर मतभेद बरकरार हैं।

माया : *मतभेद बरकरार ही नहीं, हाल में बहुत उग्र हो गये थे। मसलन प० बंगाल के पंचायत चुनावों में। आज दोनों पार्टियां तो प० बंगाल और केरल में संयुक्त साझा सरकार में शामिल हैं। फिर ऐसा टकराव क्यों?*

राव : जब दो पार्टियां रहेंगी, तो चुनाव में प्रतिद्वंद्विता होना स्वाभाविक है। प० बंगाल के पंचायत चुनावों में २००० सीटों पर समझौता हुआ था, किंतु उनमें से १००० सीटों पर मार्क्सवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था। कुछ लोगों को अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी दे दिया। बाद में इनमें से जो जीते, उनमें अनेक को उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया।

माया : *क्या इसका अर्थ है कि मार्क्सवादियों ने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की?*

राव : धोखाधड़ी की जगह मैं यह कहूंगा कि वे हमें काटना चाहते थे।

माया : *क्या इसका मूल कारण यह है कि मार्क्सवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है?*

राव : मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राजनीति में कोई किसी का बड़ा भाई नहीं है। हमारे देश की स्थिति यह है कि छोटी-से-छोटी पार्टी भी जीवित रह सकती है, यदि वह अवाम के साथ जुड़ी हो। जब दो पार्टियां होती हैं, तो प्रतिद्वंद्विता तो होती ही है।

माया : *त्रिपुरा की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि मार्क्सवादी पार्टी का यह आरोप कि वहां सेना बुलाने और मतदान में गड़बड़ी से कांग्रेस जीती है, सही नहीं है। मार्क्सवादी पार्टी अपनी कमजोरी से हारी है।*

राव : इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में पार्टी की राज्य समिति में जो विचार-विमर्श हुआ, उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

माया : *आपकी पार्टी आगे बढ़ने की जगह पीछे जाती क्यों लग रही है?*

राव : आगे-पीछे जाने का मापदंड आज यही हो गया है कि कोई पार्टी कितनी सीटें जीती या हारी है। यह मापदंड सही नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि आप वोट तो हासिल कर सकते हैं, सीटें नहीं। कांग्रेस नेहरू के समय से ४५ फीसदी वोट पाकर ६०-७० प्रतिशत सीटें हासिल करती रही है। पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को ४९ प्रतिशत मत मिले थे और सीटें लगभग ८० प्रतिशत। इस प्रकार मौजूदा चुनाव प्रणाली के जरिए किसी पार्टी का ५ फीसदी वोट बढ़ जाने पर लगता है कि वह बहुत बढ़ गयी और उतने ही वोट घट जाने से लगता है पार्टी बहुत घट गयी है। यदि चुनाव में समानुपातिक प्रणाली कायम हो जाये, तो चुनावी अवसरवाद समाप्त हो जायेगा और पार्टियों की सही ताकत उभर कर सामने आयेगी।

माया : *पार्टी की शक्ति का परिचायक केवल चुनाव नहीं, किंतु जनांदोलन भी होता है। आपकी पार्टी, जिसने एक समय भूमि हथियाओ आंदोलन, बेरोजगारी के खातमे का अभियान आदि व्यापक पैमाने पर चलाये थे, आज लगभग खामोश क्यों है?*

राव : कुछ सवालों के ऊपर तो हम ऐसे खामोश नहीं हैं। खासकर जब देश की एकता-अखंडता की बात आती है। पंजाब में हम लोगों के पास जो हथियार थे, उनके सहारे लड़े। मणिपुर में जब नागाओं ने पृथकतावादी आंदोलन चलाया, तब भी हमारी पार्टी ने उनसे लोहा लिया। मजदूर वर्ग के मसलों को उठाने में भी हम काफी आगे हैं। भूमि के मसले पर हमारा काम थोड़ा कम अवश्य है। इसका कारण है कि अब जमींदार नये किस्म की रणनीति अपनाने लगे हैं। जहां बुर्जुवा पार्टी की सरकारें हैं, वहां वे शासक दल को इस्तेमाल करते हैं। जहां हमारी सरकार थी, मसलन केरल में अच्युत मेनन की सरकार और मार्क्सवादी पार्टी की जहां-जहां सरकारें हैं—वहां-वहां कारगर ढंग से भूमि सुधार लागू हुए हैं। प० बंगाल में भूमि का मालिकाना हक भूमिहीनों को मिल रहा है। बुर्जुवा पार्टी के शासन वाले राज्यों में जमींदार सत्ताधारी पार्टी, कानून व पुलिस का इस्तेमाल करने के साथ-साथ अपनी सेनाएं भी बना रही हैं और गरीब मजदूरों की हत्या करते हैं, गैरकानूनी बेदखली करते हैं। ऐसी नौबत आ गयी है कि कई जगहों पर हथियार उठाकर अपनी रक्षा करनी पड़ती है।

माया : *किंतु कहा जाता है कि जब-जब कांग्रेस जैसी बुर्जुवा पार्टी कमजोर हुई है, तब-तब कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ दिया और वह भी विदेशी ताकतों के इशारे पर। ऐसा क्यों?*

राव : यह हम पर लगाया गया बड़ा पुराना इलजाम है। अब तो यह मार्क्सवादी पार्टी पर भी लग रहा है। हमने जब-जब कांग्रेस का साथ दिया, तब किसी सिद्धांत को लेकर ही। मसलन हाल में जब जैल सिंह राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी की सरकार को बरखास्त करने की सोच रहे थे, तो हम दोनों पार्टियों ने खुलेआम जैल सिंह से कहा कि संविधान के अंतर्गत आपको बहुमत प्राप्त दल की सरकार को बरखास्त करने का अधिकार नहीं है। राजीव गांधी के प्रति

> **हमने जब-जब कांग्रेस का साथ दिया, तब किसी सिद्धांत को लेकर ही। मसलन हाल में जब जैल सिंह राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी की सरकार को बर्खास्त करने की सोच रहे थे, तो हम दोनों पार्टियों ने खुलेआम जैल सिंह से कहा कि संविधान के अंतर्गत आपको बहुमत प्राप्त दल की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। राजीव गांधी के प्रति हमारी हमदर्दी नहीं है, पर हम यह मानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के आधार पर ही हम भारत की एकता को बरकरार रख सकते हैं।**

हमारी हमदर्दी नहीं है, पर हम यह मानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के आधार पर ही हम भारत की एकता को बरकरार रख सकते हैं। किंतु यह दुष्प्रचार हो गया कि गोर्बाचिव साहब ने हम दोनों पार्टियों से कह दिया, इसलिए हमने ऐसा किया। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में जब जैल सिंह को उम्मीदवार बनाने की बात आयी तो हमने कहा कि जो व्यक्ति संसदीय लोकतंत्र को खतम करना चाहता है, उसे दुबारा राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए। हमने अपना यह मत खुलेआम विपक्षी पार्टियों के सामने पेश कर दिया था। जब जैल सिंहजी को हम लोगों के इस फैसले का पता चला और समझ गये कि जीतने की उम्मीद नहीं है, तो वह पीछे हट गये। फिर हम दोनों पार्टियों पर वही पुराना आरोप लगा। आज हम दोनों पार्टियां राजीव गांधी को हटाना चाहती हैं, तो यह क्यों नहीं कहा जाता है कि यह भी गोर्बाचिव साहब ने ही कह दिया है? यह दूसरी बात है कि उसका (सोवियत संघ) इस मामले में हमारे विचार से कुछ मेल नहीं खाता।

माया : ***क्या आज भी आप लोग सोवियत संघ और चीन की राय की कद्र करते हुए उनके कहने पर चलते हैं?***

राव : कम्युनिस्ट आंदोलन में कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के कहने पर नहीं चलती। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हम सम्मानित लोगों से सलाह ले सकते थे, किंतु बाद में यह बात नहीं हुई। हर पार्टी अपना निर्णय स्वयं लेती है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो।

माया : ***तो फिर ऐसे आरोप आप पर क्यों लगते हैं?***

राव : इसमें हम क्या कर सकते हैं?

माया : ***घटनाएं गवाह हैं कि जब-जब श्रीमती गांधी पर विपत्ति आयी, तब-तब आपकी पार्टी ने उनका साथ दिया।***

राव : केवल हमी ने साथ नहीं दिया। जब श्रीमती गांधी की सरकार अल्पमत में थी, तो मार्क्सवादी पार्टी ने भी उनका साथ दिया था। क्योंकि हम ऐसा न करते, तो एक प्रतिक्रियावादी सरकार के सत्तारूढ़ होने का खतरा था। हमने समझा था कि इंदिरा गांधी प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगी। वैसे सरकार की विदेश नीति मोटे तौर पर सही है, उसका हम समर्थन करते हैं।

माया : ***आप कांग्रेस की विदेश नीति का तो समर्थन करते हैं, लेकिन घरेलू नीति का विरोध। यह अंतर्विरोध क्या आपके लिए समय-समय पर हानिकर नहीं होता है?***

राव : यह सही नहीं है। हमारी नीति में अंतर्विरोध कतई नहीं है। यह सरकार भारत के सरमायेदार तबके की सरकार है। यह सरमायेदार तबका दुनिया में अमन भी चाहता है और भारत की जनता को लूटना भी चाहता है। उसकी इस रणनीति के संदर्भ में हमारी मौजूदा रणनीति में भी कोई अंतर्विरोध नहीं है।

माया : ***पंजाब में आपकी पार्टी की कुर्बानी जगजाहिर है। इस समस्या के समाधान के आपके वैकल्पिक सुझाव क्या हैं?***

हमारी पार्टी ने पंजाब में आत्मसुरक्षा टुकड़ियां बनाने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत हमने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल—लोंगोवाल आदि पार्टियों के लड़ाकू कार्यकर्ताओं की सुरक्षा समितियां बनायी जायें। नागालैंड में ऐसी आत्मरक्षा समितियां काफी कारगर साबित हुई थीं। हमने अच्छे हथियार भी मांगे थे, किंतु सिर्फ दो कार्बाइन ही हमें केंद्र सरकार से मिली हैं तथा हम पुराने हथियारों से ही लड़ रहे हैं। सरकार को सफलता तभी मिलेगी, जब वह अवाम को साथ लेगी।

राव : हमने कुछ वैकल्पिक सुझाव दिये हैं। पहली बात आतंकवादियों को पाकिस्तान और अमरीकी साम्राज्यवाद की जो मदद हासिल है, उसे खतम करने के लिए जनता को साथ लेना जरूरी है। यदि हम सशस्त्र सेना द्वारा उसे दबाना चाहें, तो यह संभव नहीं है। हम लोग विभिन्न पार्टियों के साथ आतंकवादियों के खिलाफ रैलियां आदि आयोजित कर रहे थे, तभी हरियाणा के चुनाव आ गये और केन्द्र ने बरनाला सरकार को भंग कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस न हरियाणा का चुनाव जीत सकी, न आतंकवादियों को कुचल सकी। इसका फल हुआ कि आतंकवाद विरोधी जो एकजुट संघर्ष चल रहा था, वह पिछड़ गया। अब उस प्रकार का संयुक्त अभियान नहीं चल रहा है। इसी प्रकार जोधपुर नजरबंदों का मसला है। उस समय जो लोग स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने भी गये थे और जो पूरी तरह निर्दोष थे, उन्हें भी आतंकवादियों के साथ पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हम उसी समय से मांग करते आ रहे हैं कि जांच पड़ताल करके जो लोग आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाये, किंतु उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया। तीसरा मसला १९८४ के दंगे हैं। उस समय सिखों पर बहुत जुल्म हुआ। रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी कहा है कि उस दौरान लगभग तीन हजार सिख मारे गये। उस सिलसिले में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी पार्टी ने पंजाब में आत्मसुरक्षा टुकड़ियां बनाने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत हमने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल-लोंगोवाल आदि पार्टियों के लड़ाकू कार्यकर्ताओं की सुरक्षा समितियां बनायी जायें। नागालैंड में ऐसी आत्मरक्षा समितियां काफी कारगर साबित हुई थीं। हमने अच्छे हथियार भी मांगे थे, किंतु सिर्फ दो कार्बाइन ही हमें केंद्र सरकार से मिली हैं तथा हम पुराने हथियारों से ही लड़ रहे हैं। सरकार को सफलता तभी मिलेगी, जब वह अवाम को साथ लेगी।

माया : ***हाल में आप अपने साथियों सहित चीन गये थे। वर्षों बाद बने चीन से आपके संबंधों का कारण क्या है?***

राव : अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन माओत्से तुंग के तीसरे महायुद्ध के बारे में इस विचार को लेकर ही हुआ था कि विश्वयुद्ध के बाद बची आधी आबादी समाजवादी हो जायेगी। इसे अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने नहीं माना था। बाद में हमारे देश के विषय में उनकी राय और हमारी पार्टी की राय में भी मतभेद था। तिब्बत में चीन के प्रवेश के बाद दलाई लामा जब भारत आये, तो उस समय चीन के नेताओं की भारत सरकार के बारे में समझदारी गलत थी। उनकी धारणा थी कि अमरीकी साम्राज्यवादियों के इशारे पर यह सरकार चल रही है और इसीलिए उसने दलाई लामा को शरण दी है। फिर सीमा संघर्ष होने लगे। उसी दौरान पार्टी महासचिव अजय घोष के नेतृत्व में १९५९ में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। भारत में माओत्से तुंग का कहीं पुतला जलाया

गया था, जिसका माओ ने जिक्र किया था। अजय घोष ने कहा कि हमारे देश में तो लोग संविधान तक को जला देते हैं, क्योंकि वहां लोकतंत्र है। किंतु वे लोग नहीं समझे। एक वायदा अवश्य किया कि जारी सीमा विवाद में वे (चीन) मैकमोहन रेखा पार नहीं करेंगे। बाद में हमारी संसद में बहुत बकवास चला। इस पर चीन ने पंडित नेहरू को 'सबक सिखाने' के लिए हमला कर दिया। उसके बाद से चीन से हमारा संबंध टूट गया। अब उनकी अंतरराष्ट्रीय लाइन बदल गयी है। वे मानते हैं कि परमाणु युद्ध रोकना चाहिए। वह अमरीकी साम्राज्यवाद की चालों को नाकाम करने के लिए अनेक क्षेत्रों में सक्रिय भी हैं। साथ ही चीनी प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत करने के बाद स्पष्ट हुआ है कि चीनी नेतृत्व अपने देश का आधुनिकीकरण करने में लगा है।

माया: ***क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा वैसे-वैसे आपकी पार्टी चीन के साथ निकट संपर्क बनाती जायेगी?***

राव: अभी हम थोड़ा नजदीक आये हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे मतभेद बरकरार हैं। मसलन कंपूचिया और वियतनाम के बारे में। किंतु कई अन्य मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने पर हम निकट आये है, जैसे सीमा विवाद। चीन ने हमें आश्वासन दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को वह पार नहीं करेगा और उसका पालन करेगा। उसने भारत से आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने की पेशकश भी की है।

माया: ***क्या आप दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो एकता बढ़ायी है, उसके परिणामस्वरूप आपकी पार्टी थोड़ा चीन की ओर और मार्क्सवादी पार्टी सोवियत संघ की ओर बढ़ रही है?***

राव: ऐसी बात नहीं है। चीनी नेतृत्व की नीति में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण हमने उनसे संबंध बनाये हैं।

माया: ***और सोवियत संघ ने मार्क्सवादी पार्टी से अपने संबंध क्यों बनाये हैं?***

राव: मार्क्सवादी पार्टी ने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने रुख को बदला है। इसीलिए वह भी अब सोवियत संघ के साथ है।

माया: ***एक बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता के रूप में शासक दल और गैरकम्युनिस्ट विपक्ष पर आपकी प्रतिक्रिया?***

राव: जहां तक शासक दल का प्रश्न है, राजीव गांधी की आर्थिक नीति बहुत गलत और देश के लिए घातक है। मसलन सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजा खोलना। इन कारणों से हमारे निजी और सार्वजनिक उद्योग का बहुत नुकसान हो रहा है। राजीव गांधी की नीतियों के खिलाफ छोटे सरमायेदार भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। अविवेकपूर्ण कंप्यूटरीकरण से और भी बेरोजगारी फैलेगी। यद्यपि कांग्रेस ने लोगों को बहकाने के लिए तमिलनाडु के अपने हाल के अधिवेशन में गरीबी हटाओ के साथ बेकारी हटाओ का भी नारा लगाया है। उनकी ऐसी जनविरोधी नीतियों के कारण ही हम उनका विरोध कर रहे हैं।

जहां तक गैरकम्युनिस्ट विपक्ष का सवाल है, हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियों से संबंध विच्छेद करें। क्योंकि संप्रदायवाद देश को तबाह करने पर उतारू है। मसलन जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम फिरकापरस्त और पंजाब के कट्टरवादी सिख इसी रास्ते पर चल रहे हैं। साथ ही हिंदू संप्रदायवाद भी अत्यधिक घातक है। जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाये? उसके एक-एक नेता की एक-एक पार्टी लगती है। सबकी अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग है।

माया: ***राजीव गांधी ने उसी अधिवेशन में कहा है कि कम्युनिस्ट सत्तर साल पुरानी किताब के अनुसार चल रहे हैं।***

राव: वह किताब क्या है, उन्हें शायद यह भी मालूम नहीं। वह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है या 'दास कैपिटल' (मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक-पूंजी)? राजीव गांधी को कोई 'ब्रीफ' कर रहा है और वह बोल रहे हैं। उनके काम करने के तौर-तरीके ठीक नहीं हैं। इस ढंग से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। आज नौबत यहां तक आ गयी है कि मणिपुर में रात साढ़े १२ बजे मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करता है। एक रात के अंदर मध्य प्रदेश और बिहार में ६० विधायकों को जगाया जाता है और सर्वसम्मत फैसला कहकर अर्जुन सिंह और भागवत झा आजाद को कुरसी सौंप दी जाती है। उसी प्रकार भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप चाहे तो तथ्य पेश कीजिए, वह तकनीकि तरीके से बहस करते हैं। किंतु बोफोर्स और जर्मन पनडुब्बियों के सौदे के बारे में दिन-प्रतिदिन जो आ रहा है, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। इन सब कारणों से हमने राजीव गांधी से इस्तीफा देने और पुनः चुनाव कराने की मांग की है।

माया: ***गैर कम्युनिस्ट विपक्ष के बारे में आपका क्या विचार है?***

राव: जहां तक गैरकम्युनिस्ट विपक्ष का सवाल है, हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियों से संबंध विच्छेद करें। क्योंकि संप्रदायवाद देश को तबाह करने पर उतारू है। मसलन जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम फिरकापरस्त और पंजाब के कट्टरवादी सिख इसी रास्ते पर चल रहे हैं। साथ ही हिंदू संप्रदायवाद भी अत्यधिक घातक है। जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाये! उसके एक-एक नेता की एक-एक पार्टी लगती है। सबकी अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग है। लोकदल-ब नेता देवीलाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो चुन लिया है, नाम चुनना बाकी है।

माया: ***आपको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भविष्य कैसा दिखायी दे रहा है?***

राव: भविष्य उज्ज्वल है। हमारा देश की जनता पर पूरा विश्वास है। वही भारत को बचायेगी।

माया: ***खबर है आप पार्टी महासचिव पद छोड़ रहे हैं और एक उपमहासचिव पद बनाया गया है।***

राव: हां, २५ वर्ष तक मैं इस पद पर था। अब रिटायर हो रहा हूं। अगले महासचिव का परिचय कराने के लिए एक उपमहासचिव पद भी बनाया गया है। पर इसकी एक प्रक्रिया है। अगले साल पार्टी कांग्रेस में रिटायर हो जाऊंगा।

माया: ***आज रिटायर होने का समय नजदीक है, तो पीछे मुड़कर देखने पर आपको कैसा लगता है?***

राव: पिछले २५ साल तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी भी मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं।

—रंजना कक्कड़/ त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

मेरी दुनिया ही पलट जाती...

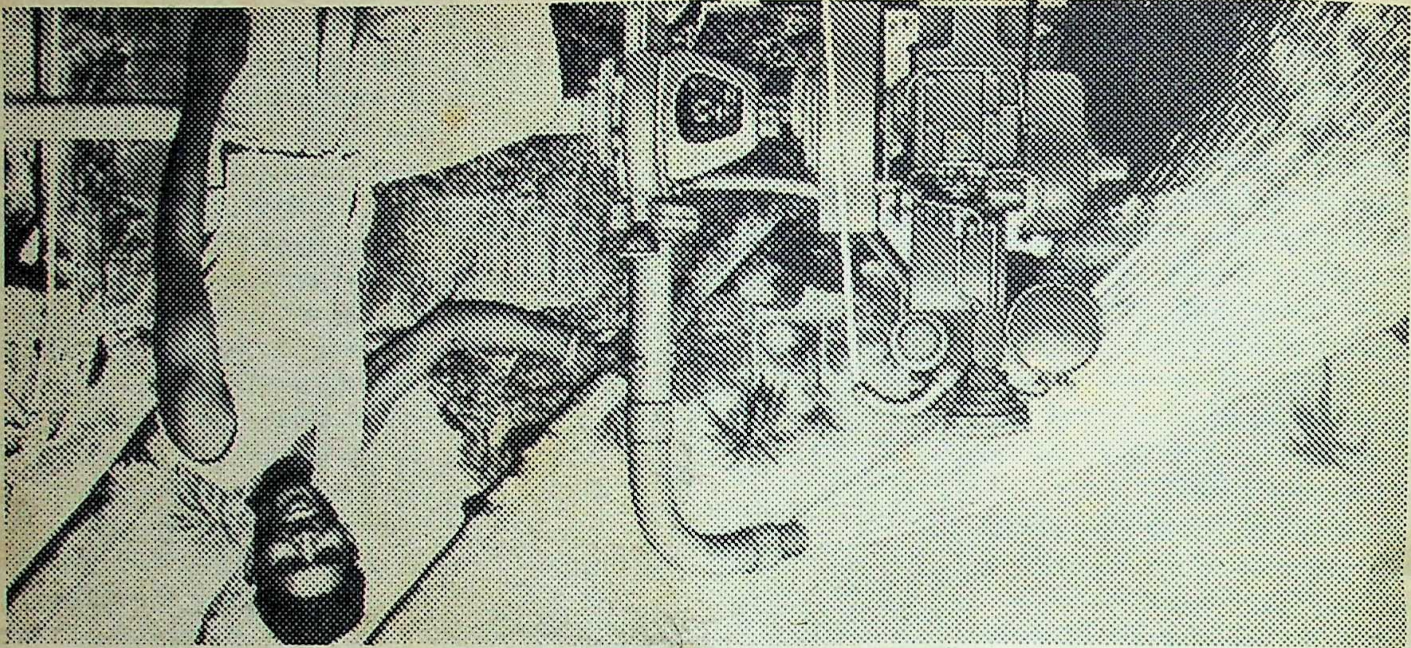

अगर मैं न्यू इन्डिया से पम्पसेट का बीमा न करवाता.

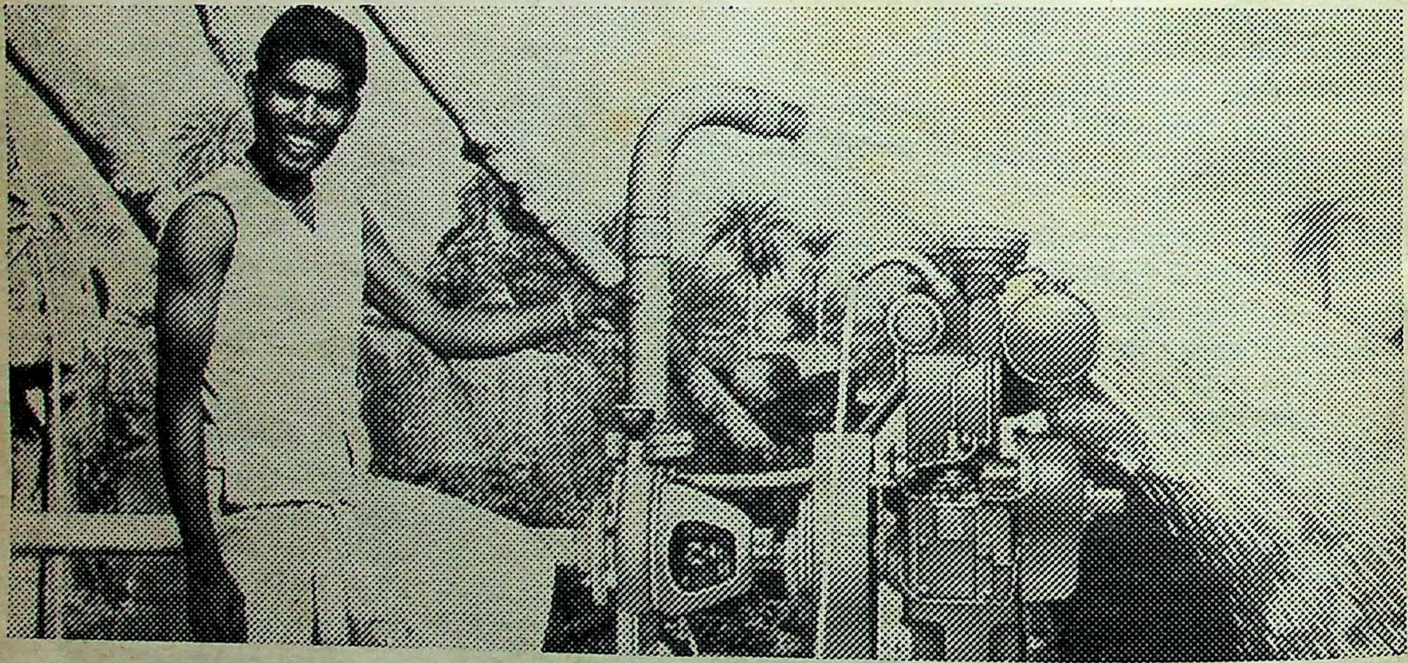

मेरा पम्पसेट चोरी हो गया लेकिन काम नहीं रुका. क्योंकि न्यू इन्डिया की बदौलत मैं नया पम्पसेट लगवा सका.

एक किसान के लिए उसका पम्पसेट कितना मूल्यवान होता है, यह बात वह और उसके परिवारवाले अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन वही पम्पसेट अगर जल जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए... या चोरी हो जाए तो? ऐसे में, न्यू इन्डिया एश्योरन्स एक सच्चे मित्र की तरह उसका सहारा बनता है.

पम्पसेट बीमा – न्यू इन्डिया एश्योरन्स का मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से सालभर में 50 रुपए से 190 रुपए तक देने पड़ते हैं... बस! देशभर में न्यू इन्डिया एश्योरन्स के लगभग 1000 कार्यालय हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही एजेंट से मिलें या अपने नज़दीकी कार्यालय में पधारें.

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

जनरल इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी

पम्पसेट बिमा – नुकसान में आपका सहारा!

R.K.SWAMY/NIA/3573B/HIN

स्वर्ण मंदिर से मिली लाशों का रहस्य

श्रद्धास्थल बेगुनाहों की कब्रगाह बन गया था: स्वर्ण मंदिर परिसर का एक खण्ड

आपरेशन ब्लैक थंडर के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों के सफाये के बाद जब हरमंदिर साहब की मर्यादा बहाल करने और परिसर की सफायी करने का काम शुरू हुआ, तो ऐसे तथ्य उजागर होने लगे, जिन्हें देख-सुनकर कलेजा कांप जाता है। सिख धर्म के इतिहास में स्वर्ण मंदिर में कभी ऐसा घृणित काम नहीं हुआ, जैसा उन आतंकवादियों ने किया जो सिख धर्म के स्वयंभू रक्षक होने का दावा करते हुए धर्मप्राण सिखों की आस्था का दोहन कर रहे थे। यहां प्रस्तुत हैं, वे कुछ तथ्य जो आतंकवादियों की नृशंसता के गवाह हैं:

तीर्थयात्रियों और अधिकारियों का एक छोटा दल मंजी साहब के समीप ३० फीट ऊंचे मलबे की खुदाई को सशंकित भाव से देख रहा है। जैसे ही फावड़ों के चलने से नमक की एक बड़ी बोरी निकलती है, दर्शकों का चेहरा कठोर-गंभीर हो जाता है। एक और सड़ा-गला शव नमक की बोरियों के बीच दबा बरामद होता है। गत २४ मई के बाद वहां पाया गया, यह २४वां शव था।

अकाल तख्त की पावन मिट्टी को उन १०० से अधिक लोगों के क्षतविक्षत शरीरों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने और पुण्य कमाने आये थे। किंतु जिन्हें आतंक, अंग-भंग, बलात्कार और मौत का शिकार होना पड़ा और वह भी उन आतंकवादियों के द्वारा जिन्हें वे सिख धर्म का रक्षक समझते थे।

आतंकवादी स्वर्ण मंदिर प्रांगण को कब्रगाह के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका संकेत पहली बार अनायास इस वर्ष जनवरी में मिला था। पुलिस की गिरफ्त में आये एक आतंकवादी लड़के ने सीआरपीएफ के डीआईजी एसएस विर्क को बताया था कि मंजी साहब के पास आतंकवादियों ने एक शव को गाड़ दिया है। उस लड़के की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय पुलिस अंदर जाकर जांच करने में असहाय थी। वैसे तब तक सुरक्षा बल के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो गयी थी कि आतंकवादी मंदिर के अंदर जघन्य अपराध-कर्मों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ऐसी खबरें भी मिली थीं कि चंद दुर्दान्त आतंकवादी प्रायः जवान लड़कों पर हमले करते हैं और महिलाओं को जबरन आत्मसमर्पण के लिए विवश करते हैं। उन्हें विश्वस्त सूत्रों ने यह भी जानकारी दी थी कि मंजी साहब के समीप का कमरा नंबर ४६ और उसके बाद के क्वार्टरों का प्रायः ऐसे अपराधों के लिए प्रयोग किया जाता था। कमरा नंबर ४१ और उसके आसपास के कमरों को लूट-खसोट, मारपीट और आतंक की कालकोठरियो में बदल दिया गया था।

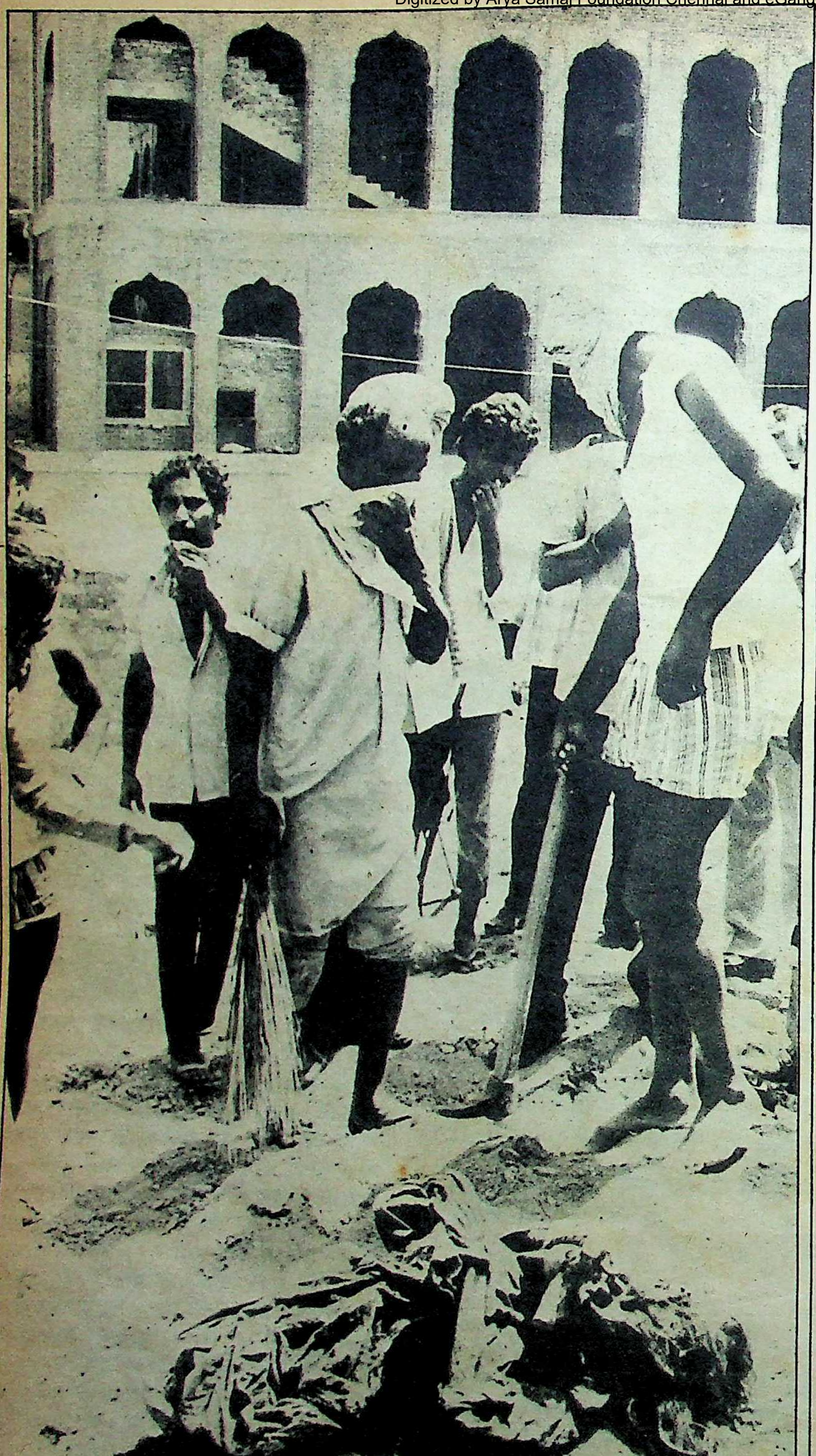

लाशें-ही-लाशें : अकाल तख्त के मलबे से निकली एक लाश

नृशंस हत्या : गुरबचन कौर

क्रूर कृत्य : संदिग्ध लोगों को नंगा करके बिजली के जलते हीटरों पर बिठाया जाता था। जब उनका मांस जलने-गलने लगता था, तो उस पर नमक-मिर्च छिड़का जाता था। संदिग्धों के शरीर के विभिन्न भागों पर बिजली के तारों से झटके दिये जाते थे। इसके सबूत में बिजली के विभिन्न हीटर (सुइयां) रबड़ के दस्ताने और नमक के पैकट तथा उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले खास किस्म के बिजली के नंगे तार एक कमरे से बरामद हुए हैं।

ऐसी बर्बर कार्रवाइयों तथा गला घोंटने से मृत लोगों का शव रात के अंधेरे में पास के मलबे में गाड़ने के लिए लाया जाता था। यह उनकी घृणित पिशाची लीलाओं के लिए आदर्श-स्थल था। यह स्थान अकाल तख्त के सामने और रामदास सराय, बाबा जोगेन्दर सिंह और अन्य उच्च-पदाधिकारियों के क्वार्टरों से घिरा होने के कारण संदेह के दायरे से बाहर और सुनसान था। दर्शन-ड्योढ़ी भी मंजी साहब के सरोवर के उस पार है। इसलिए तीर्थयात्रियों की भीड़ ज्यादातर उसी पार रहती है। अधिकांश लोग मलबे की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जो थोड़ा साहस करते भी थे, वे टीले के पीछे स्थित लंगर की छत पर बंदूकों से लैस घूमते आतंकवादियों की खूंख्वार नजरों से भयभीत हो फौरन वहां से चले जाते थे। आतंकवादियों को मंजी साहब के निकट ठिठककर जिज्ञासा और उत्सुकता से इधर-उधर देखनेवालों का फौरन पता चल जाता था। अब शवों का पता लगने के बाद कुछ लोग उन क्षणों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मलबे का क्षेत्र और आसपास के कमरों के बीच वे कैसे अपने को भयाक्रांत अनुभव किया करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि उन कमरों में लूट-खसोट और 'मुखबिरों को सजा देने' की वारदात हुआ करती हैं। दूकानदारों ने भी ऐसी अफवाहें सुन रखी थीं। इसीलिए वे परिसर में जाने से कतराते थे। खासकर गत दो वर्षों से मंजी

पैररहित कंकाल मिला : कुलदीप सिंह

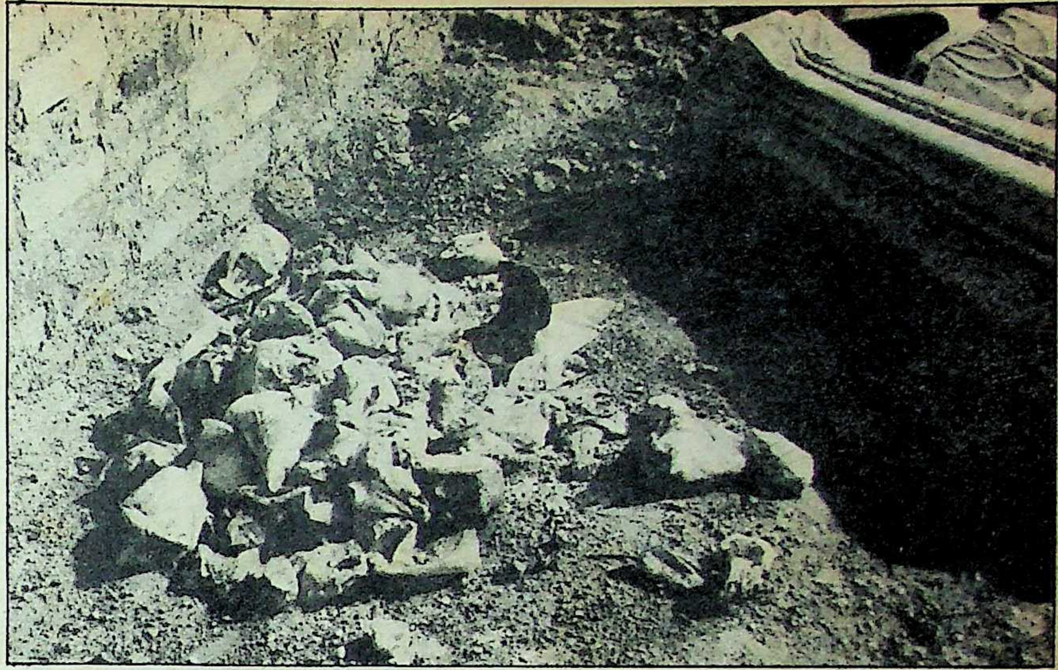

नमक की बोरियों में दबा एक शव

साहब के पास जाना उन्हें खतरे से खाली नहीं लगता था। आज लगभग नित्य-प्रति निकलनेवाले शवों से लगता है कि उनका भय सही था।

शवों की संख्या : शुरू में अधिकारियों का अनुमान था कि लगभग ३६ शव मलबे में गाड़े गये थे। बाद में गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान अधिकारियों को अहसास हुआ कि मलबे में १०० से अधिक शवों को छिपाया गया था। अनेक ऐसे परिवार, जिनके अपने सगे-संबंधी गत दो वर्षों से लापता हैं, स्वर्ण मंदिर में आकर खुदाई को देख रहे हैं। कांपते पांवों को मजबूती से जमाये, चेहरे का पसीना पोंछते और एकटक आंखों से खामोशी से धूलधूसरित मलबे की फावड़ों से हटती मिट्टी को वे देखते हैं। नाकों को रूमालों से ढके ये सब-के-सब किसी कंकाल के बरामद होते ही उसे गौर से देखने के लिए झुक जाते हैं। उस समय का दृश्य अति हृदयविदारक, कारुणिक और कठोर होता है। बुरी तरह सड़-गल चुके शव पर उनकी आंखें किसी ऐसी पहचान के लिए टिकी होती हैं जिनसे यह शिनाख्त हो सके कि यह शव उनके सगे-संबंधी का तो नहीं है।

दर्दनाक दास्तान : अभी तक जितने शव बरामद हुए हैं, उनमें से जितनों की शिनाख्त हो चुकी है, उनमें एक है, ४५ वर्षीय सेवादार गुरबचन कौर। उसका पति बेरोजगार था। परिवार में पांच लड़कियां थीं। सब का वही पेट पालती थी। वह पिछले सात सालों से अमावस्या व संक्रांति को कारसेवा के लिए बिना नागा दरबार साहब आया करती थी। १९ जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह को ८ बजे वह अपने पति के साथ मंदिर पहुंची। उसका पति तो कुछ देर बाद लौट आया, किंतु वह महिला तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए वहां रुक गयी। उसके शाम ६ बजे तक लौटने की उम्मीद थी। अंधेरा घिर आया था, फिर भी वह नहीं लौटी। परिवारवाले देर तक उसे इधर-उधर तलाशते रहे। उन्होंने उसकी खोज में पूरी रात मंदिर परिसर को छान डाला। मगर कोई अता-पता न चला। सिर्फ उसकी चप्पलें जोड़ाघर में और बैग और शाल प्रसाद घर के पास पाया गया, जहां वह महिलाओं की पंक्ति बनाने में मदद किया करती थी। परिवार का एक सदस्य जब श्रीमती कौर का पता करने कमरा नंबर ४१ में गया, तो आतंकवादियों ने उसे पूरे परिवार का सफाया करने की धमकी दी।

दूसरे दिन थाने में प्रथम साक्ष्य रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गयी, किंतु पुलिस असहाय दिखायी पड़ी। इस प्रकार गुरबचन कौर का परिवार आशा और भय के बीच झूल रहा था। वे दरबार साहब में दुबारा जाने की हिम्मत न बटोर सके, क्योंकि आतंकवादियों की धमकी क्या होती है, इसका पूरा अहसास उन्हें था। २५ मई १९८८ को जाकर उन्हें पता चला कि गुरबचन का क्या हश्र हुआ। उसका सड़ा-गला शव जो नमक की पांच बोरियों के बीच दबा था खोदकर निकाला गया। उन्होंने उसके कपड़ों से उसको पहचाना। दुपट्टे का एक कोना उसके हाथ के कड़े से बंधा था और शेष उसके गले के चारों ओर कसा था। क्या गला घोंट कर उसकी हत्या की गयी? और क्यों? वह धर्मभीरु, अधेड़ और गरीब औरत थी। उसका अपराध केवल यही बताया जाता है कि पंक्ति में खड़ी महिलाओं से छेड़छाड़ करनेवाले आतंकवादियों को उसने रोका था। उन लोगों ने अपनी 'मौज-मस्ती' में रुकावट डालनेवाली गुरबचन कौर को सबक सिखा दिया।

कुलदीप सिंह का मामला : पवित्र परिसर में उनका ही कानून जो चलता था। उनकी नाखुशी मोल लेने का मतलब जिंदगी से हाथ धोना था। इसमें वे उम्र अथवा स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते थे। एक सम्मानित वृद्ध सिख-जो अभी भी आतंकवादियों से बुरी तरह भयभीत हैं तब लगभग रो पड़े, जब 'माया' से उन्होंने बताया, "आतंकवादी स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करके स्वयं धर्म और मर्यादा को अपवित्र कर रहे थे। उन्होंने उसे यंत्रणा शिविर में बदलकर बंदूक की नोक पर हर प्रकार के पाप और दुराचरण का नंगा नाच किया।" बहरहाल, अपनी हरकतों पर उन्हें कोई पश्चाताप नहीं। रक्त-पिपासु आतंकवादियों का शिकार बने ३० वर्षीय कुलदीप सिंह की शिनाख्त उसके माता-पिता ने की। कुलदीप बिजली की फिटिंग का काम करता था। रामदास सराय के पिछवाड़े वाली गली में किराये के मकान में वह अपने छोटे भाई-बहन और माता-पिता के साथ शांतिपूर्वक रहता था। ३ मार्च, १९८७ को अपने काम पर जाते समय मंदिर में वह माथा टेकने गया। उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। लगभग १४ महीने बाद गत २६ मई को मलबे की खुदाई में उसका कंकाल मिला। मात्र ४ फुट, ४ इंच की मांसरहित सूखी काया बरामद हुई, जिसके पैर नदारद थे। आंसू बहाती, शोक से कांपती मां ने अपने बेटे कुलदीप को कपड़ों के टुकड़ों से पहचाना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महज यही कहा गया है कि मृत्यु चोटों के कारण हुई है। पूरा परिवार व्यथा और पीड़ा से जड़वत है। किसी की समझ में बात नहीं आ रही है कि उस निर्दोष की क्यों हत्या की गयी? धन वसूलने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि परिवार की ऐसी औकात ही नहीं है। फिर क्या वह अप्राकृतिक कामवासना का शिकार बना? अथवा आतंकवादियों का हुक्म बजाने से उसने इनकार कर दिया जिसकी उन्हें आदत नहीं। कारण कुछ भी हो। आज स्थिति यह है कि कुलदीप सिंह के माता-पिता की स्वर्ण मंदिर के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं है। बेटे के बिना पांव और मांसरहित कंकाल की भयावह स्मृति को एक झटके से निकाल फेंकना उनके लिए इस जिंदगी में मुमकिन नहीं। हत्या के कारणों पर खुलकर जिक्र करने से भी वे कतराते हैं। "हम तो उसे हमेशा के लिए खो ही बैठे हैं", गम में डूबे, भर्राये गले से उन्होंने 'माया' को बताया।

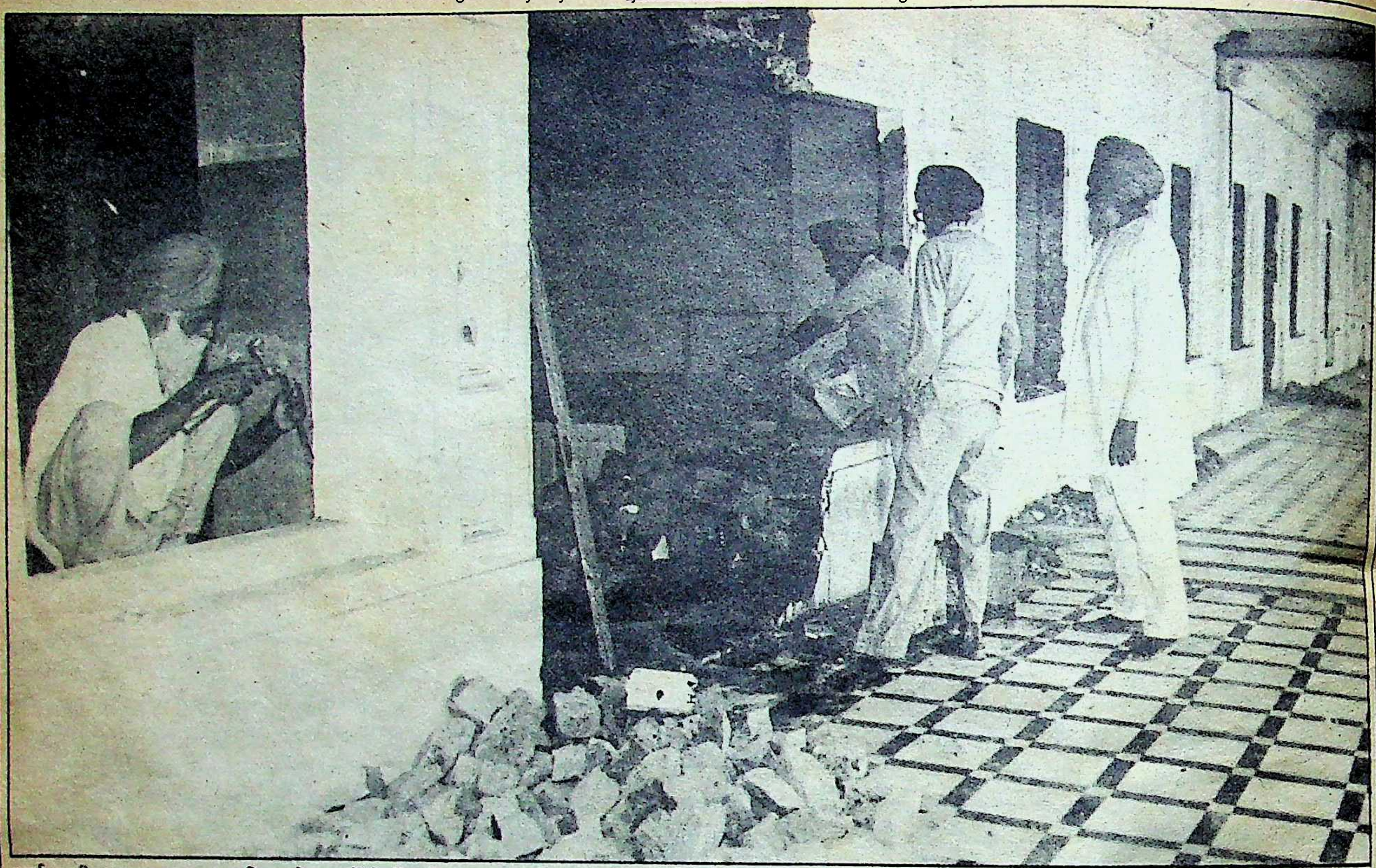

मर्यादा की रक्षा का सवाल : परिसर के कमरों से खिड़कियां व दरवाजे हटाते कारीगर

जहां तक नगर निगम के नौजवान बिल्डिंग इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की हत्या के कारणों का सवाल है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। वह मांगी गयी रकम देने में असमर्थ था। एक अन्य युवा सतिंदर पाल तो प्रेम के कारण मारा गया। वह एक ऐसी लड़की से प्यार करता था, जिसका एक आतंकवादी ढिल्लों से अवैध संबंध था। मामला जब बहुत बढ़ गया, तो सतिंदर को मंदिर में छल-बल से ले जाया गया। वहां से वह कभी नहीं लौटा। जिन दो अन्य शवों की शिनाख्त हुई है, उनमें एक कंवल सिंह और दूसरा करन सिंह था। ये दोनों अमृतसर जिले के बाहर के थे।

पुलिस और खासकर संबंधित परिवार अपने गुमशुदा सगे-संबंधियों के बारे में आज जो बातें कर रहे हैं, उनसे पता चलता है कि लापता लोगों के इतने कम मामले क्यों दर्ज हुए थे। लोग मारे डर के पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे। संभव है, पूरे टीले की खुदाई के बाद अनेक परिवारों को अपने गुमशुदा लोगों के बारें में जानकारी मिले। अमृतसर के शिव सेना अध्यक्ष पंडित किशोर चंद कहते हैं, "हो सकता है, तीन वर्ष पूर्व लापता हुए डा० बरार और अभिलाष सिंह के शव भी जमीन में गड़े हों।" किंतु क्या सुरक्षा अधिकारियों को यह जानकारी है कि डा० बरार और अभिलाष सिंह की मंदिर के भीतर हत्या की गयी थी?

अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस आयुक्त (एसएसपी) ने 'माया' से बातचीत के दौरान बताया, "हम लोगों का खयाल था कि अनेक लोगों की हत्याएं की गयी हैं, किंतु हमारे पास कोई सबूत नहीं था।" उल्लेखनीय है कि सीआरपीएफ डीआईजी एसएस विर्क को इस पवित्र तीर्थस्थल के भीतर जारी बर्बर कांडों की कुछ जानकारी थी। उन पर गत दिनों एक १४ वर्षीय लड़के ने एके-४७ रायफल से गोली दागी थी, जो आपरेशन ब्लैक थंडर अभियान का कारण बन गयी थी। एक सिख युवक को आतंकवादी मुखबिर समझकर कमरा नंबर ४६ में पूछतांछ के लिए ले गये थे। उसने अपनी नजरबंदी के दौरान एक आदमी की हत्या और बाद में शव के टुकड़े-टुकड़े किये जाने का दृश्य देखा था। वह आतंकवादियों के चंगुल से बच निकला, किंतु मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए वह पुलिस के हाथ लग गया। उसने उस हत्या की कहानी विर्क को गत जनवरी में सुनायी थी, किंतु उसका पूरा विवरण आपरेशन ब्लैक थंडर में आत्मसमर्पण करनेवाले आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान ही मिला।

बहरहाल, शवों की बरामदगी का काय अपेक्षाकृत धीमी गति से ही है। जैसाकि कम्युनिस्ट नेता सतपाल डांग कहते हैं, "इस गति से तो मलबा साफ करने में छह महीने लगेंगे।" किंतु पता चला है कि अधिकारियों ने मलबा साफ करने की अत्याधुनिक मशीनों की मांग की है, जिससे काम तेजी से निपटाया जा सके।

हरमंदिर साहब जाने के लिए दर्शन-ड्योढ़ी पार करते हुए श्रद्धालु कनखियों से मंजी साहब को देखते हैं। स्वयं हरमंदिर साहब के अंदर अंतिम टोलीवाले आतंकवादियों ने बुरी तरह गंदगी फैलाई थी। उनके द्वारा मलमूत्र से भरे गये कनस्तरों को स्वयंसेवक वहां से हटाने में लगे थे।

स्वर्ण मंदिर में २० वर्षों से रहनेवाले एक ग्रंथी ने दबे स्वर में कहा, "मैं यहां होनेवाली हर घटना का साक्षी था, किंतु मैं मुंह नहीं खोल सकता था। चारों तरफ बंदूकों का साया जो था।" यह कहने के बाद उसने लंगर की ओर ऐसी सशंकित दृष्टि से देखा मानो आतंकवादी उस पर गोली बरसाने के लिए करीब ही खड़े हों।

आतंकवादी वहां से चले गये हैं, किंतु उनके बर्बर और जघन्य अपराधों की काली छायाएं वहां अभी भी मंडरा रही हैं। यह पावन तीर्थ स्थलों के अंदर धर्म और विश्वास के नाम पर होनेवाली घृणित करतूतों की याद ताजा करती हैं। "मैं वहां जीते जी कभी नहीं जाऊंगी," गुरबचन कौर की चौथी बेटी ने चीखते हुए कहा, जिसके अश्रुपूरित चेहरे पर विषाद की गहरी रेखाएं खिची थीं। जैसे-जैसे नरकंकाल बरामद हो रहे हैं, वैसे-वैसे गुरबचन की बेटी जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार चोट का निशाना मन नहीं, धर्म बना है।

नबनीता सरकार

छाया : सुनील सक्सेना

मैं नहीं, जनता जीती है: जीत के बाद वीपी सिंह

छाया: राजेंद्र कुमार

ऐतिहासिक चुनाव कैसे जीता गया?

जिस इलाहाबाद के उपचुनाव पर देश-विदेश की निगाहें टिकी हुई थीं, वह जिस घमासान तरीके से लड़ा गया, उसकी मिसाल आजादी से अब तक नहीं मिलती। एक ओर कांग्रेस-इ पूरे लाव-लश्कर के साथ यहां जूझ रही थी, तो दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष टक्कर ले रहा था। अंततः जीत संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुई। इस चुनावी महाभारत में कांग्रेस-इ ने कौन-कौन से 'हथियार' इस्तेमाल किये और वे कारगर सिद्ध क्यों नहीं हुए? राजा ने यह महाभारत कैसे जीता? इस उपचुनाव से जुड़े सभी पक्षों पर 'माया' की टीम का विस्तृत जायजा और विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण:

मतगणना शुरू होने में अभी एक घंटे का समय बाकी था। इलाहाबाद के सर्किट हाउस के वीआईपी कक्ष में सोफे पर सीताराम केसरी पलथी मार कर बैठे थे। पास बैठे पत्रकार ने उनसे पूछा, "बताइए केसरीजी आपका क्या खयाल है?" केसरी ने पत्रकार की जांघ पर धौल जमाते हुए फरमाया, "जीत तो हमारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है।"

मतगणना शुरू होने में अभी साढ़े छह घंटे बाकी थे। रात के एक बजे उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण मंत्री 'यात्रिक होटल' के शीतित कमरे में खाने के बाद अपने दांत कुरेद रहे थे। सामने टेबल पर जूठन से भरी प्लेटें रखी थीं। पलंग पर और अन्य जगहों पर लगभग १५ 'मजबूत' कार्यकर्ता बैठे थे। जब पूछा गया कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने छूटते ही कहा, "वीपी सिंह ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस-इ हेराफेरी करेगी, ताकि हार के बाद कह सकें कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भारी हेराफेरी हो रही है।" इन्हीं मंत्री महोदय ने तीन-चार बार पहले सर्किट हाउस में कहा था, "इस चुनाव का परिणाम पत्रकारों के लिए 'स्टार्टलिंग' (चौंकानेवाला) होगा" यानी उनकी जीत अटल है।

२३ मई से चुनाव की कमान थामे बैठे कांग्रेस-इ के बड़बोले महासचिव गुलाम नबी आजाद ने चुनाव के दो दिन पहले सरेआम कहा, "हम एक लाख से जीत रहे हैं।"

महाप्रबंधक के रूप में पधारे रक्षा राज्यमंत्री संतोष मोहन देव चुनाव के ऐन मौके तक आश्वस्त थे कि जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा में चुनाव जीता है, उसी तरह अपनी महारत से वह इलाहाबाद का चुनाव अवश्य जीत लेंगे। हां, जीत का अंतर उनकी दृष्टि में ऐसा था, जैसे उन्होंने पहले से ही मत-पत्रों की गिनती कर ली हो, "हम १२ हजार वोटों से जीतेंगे।"

इतना ही नहीं, विदेश यात्रा में साथ गये पत्रकारों के लौटते समय स्वयं प्रधानमंत्री और कांग्रेस-इ के अध्यक्ष राजीव गांधी ने बताया, "हमारी पार्टी इलाहाबाद में चुनाव जीत चुकी है। जिनको यह बात समझ में नहीं आती, वे अपना दिमाग ठीक कर लें।"

अद्भुत आत्मविश्वास से भरे इन दावों को सुन-पढ़ कर लगा, राजा को जिसे हाथ की सफाई का डर था, वह सही होने जा रहा है। जबकि यह कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि राजा हार रहे हैं। १६ जून को हर पोलिंग बूथ का वातावरण ही बता रहा था कि राजा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, उनमें भी जहां राजा कमजोर माने जा रहे थे, जिस भी मतदाता से पूछा गया,

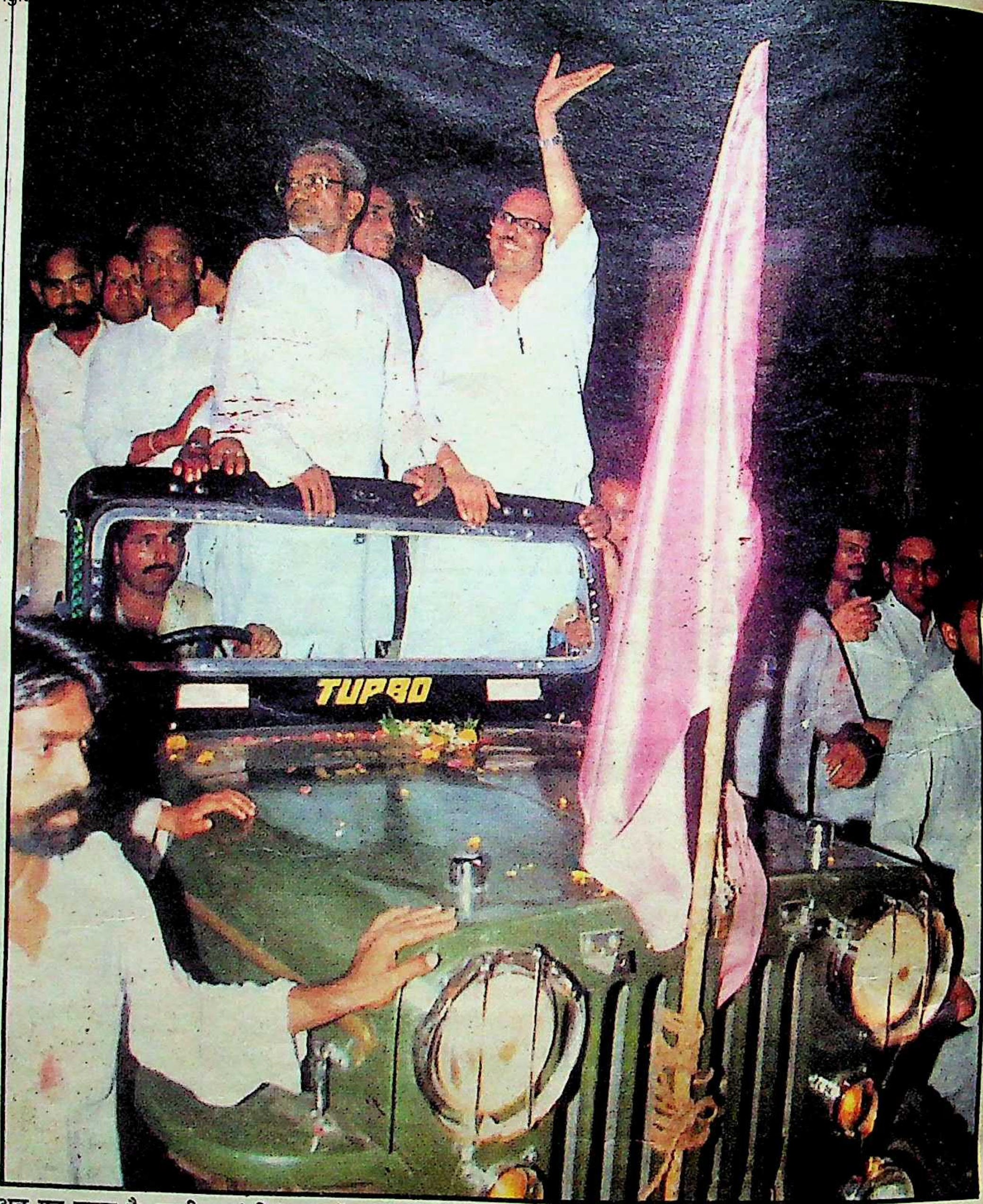

अब यह स्पष्ट है, राजीव गांधी भ्रष्ट हैं: विजय जुलूस

छाया: राजेंद्र कुमार

विजय नृत्य

छाया: वसीमुल हक़

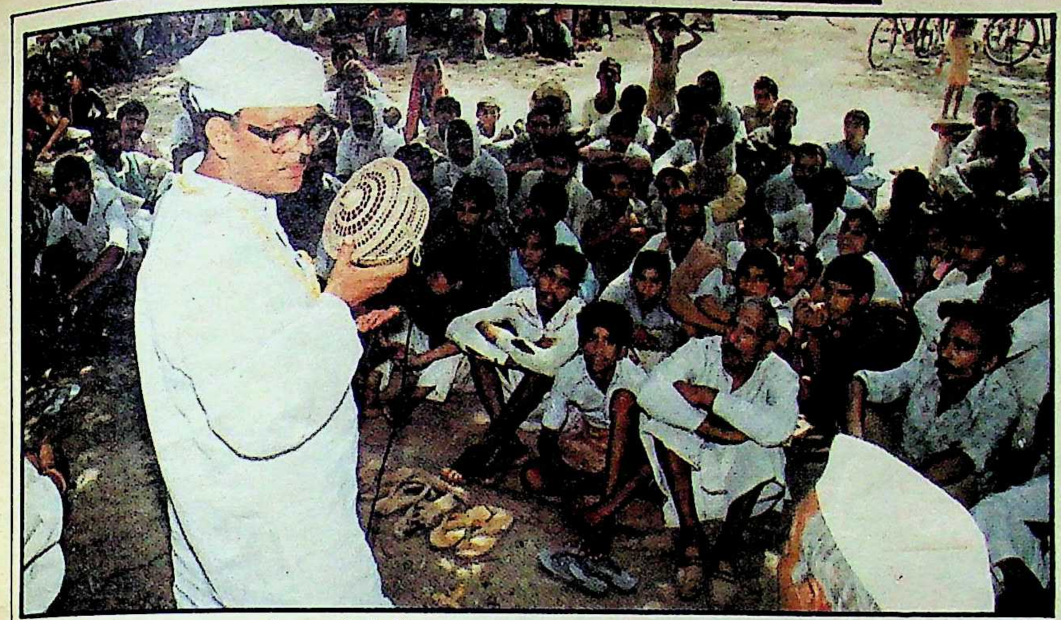

चुनाव के समय अलख जगाते हुए वीपी सिंह

छाया: मनमोहन शर्मा

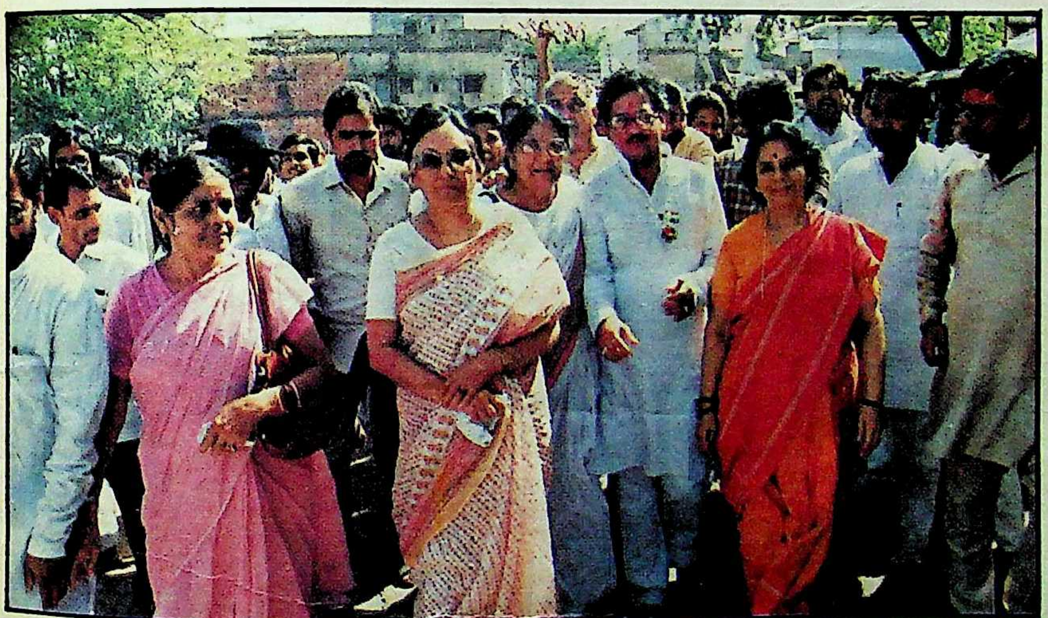

मतदाता पर कम, कैमरे पर ज्यादा ध्यान: सुनील शास्त्री पदयात्रा के समय

छाया: मनमोहन शर्मा

जातपांत के आंकड़े धरे रह गये: कांशी राम मतगणना के समय

छाया: मनमोहन शर्मा

उसने एक ही जवाब दिया नंबर दो और तीन की लड़ाई चल रही है। "नंबर एक पर कौन है?" जब यह पूछा जाता था, तो एक ही जवाब मिलता था कि क्या आपको मालूम नहीं है? लोग यह मान कर चल रहे थे कि राजा तो नंबर एक पर हैं ही, नंबर दो पर सुनील शास्त्री रहेंगे या कांशीराम, इसी के लिए मतदान हो रहा है।

लेकिन इसके बावजूद केसरी और आजाद का १७ जून तक यह दावा कि सुनील एक लाख मतों से जीत रहे हैं, इस बात की पुष्टि करता था कि 'हाथ की सफाई' काम कर चुकी है। इसी कारण १७ जून को ८ बजे शाम को जब राजा पहले दौर में ९ हजार मतों से आगे थे, तब भी यह भय बना हुआ था कि कहीं पलड़ा उलट तो नहीं जायेगा। लेकिन इसी के बाद जब १७ जून को ही दिल्ली दूरदर्शन पर एक सर्वेक्षण के जरिये चुनाव की दिशा दिखायी गयी कि वीपी सिंह एक लाख मतों से जीत सकते हैं, तब कचहरी पर जमे राजनीति-प्रेक्षकों और देश-विदेश से आये संवाददाताओं को यह लगा कि दिल्ली ने इलाहाबाद में जमे केसरी और आजाद जैसे कांग्रेसी महारथियों को यहं इशारा कर दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मतगणना सही होने में ही भलाई है। महीने भर के घमासान चुनावी दौर में यह पहला सही और संजीदा कदम लगा। लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि यहां का माहौल इतना सनसनी भरा था कि मतगणना केंद्र के सामने छह-सात हजार लोगों की भीड़ थी। जिस समय मतगणना का मुआयना करने वीपी सिंह आये, तो उस समय २०-२५ युवकों (बाहुबली नहीं) की टोली सिनेमाई अंदाज में नाचती हुई आयी। वे युवक नारे लगा रहे थे: राजा जीत गये, राजीव का चमचा हार गया। थोड़ी देर में २०-२५ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के एक मंत्री और प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी आये, तो 'ग्रीन ब्रिगेड' के एक सदस्य और हरियाणा के विधायक ने उन्हें रोक कर कहा, "हमें मालूम है आप क्या करने आये हैं। आप चाहते हैं कुछ बलवा हो और मतगणना स्थगित हो जाये। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप मारने आये हैं और हम मरने।" जनता की इस भाव भंगिमा को देखते हुए कोई हाथ की सफाई अब नहीं चल सकती थी।

परिणामस्वरूप १८ जून को रात पौने नौ बज़े दूरदर्शन के सीधे प्रसारण में इलाहाबाद के जिलाधीश पीसी चतुर्वेदी ने घोषणा की. "निर्दलीय उम्मीदवार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को १ लाख १० हजार मतों से मैं विजयी घोषित करता हूं।" इस समय तक वे कांग्रेसी सिपहसालार अपने वातानुकूलित कमरे खाली कर चुके थे, जिनके बारे में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता निरंतर कह रहे थे, "वे चुनाव-प्रचार के लिए नहीं, पिकनिक के लिए आये हैं... उनका एक मात्र उद्देश्य फोटो खिचवाकर अखबारों में छपवाना है, ताकि राजीव गांधी देख सकें कि उन्होंने किस कदर खून-पसीना एक किया है।" दूसरी ओर पूरे शहर में रात के ढाई बजे तक दीवाली-होली-ईद जैसा माहौल था। शहर के प्रमुख

मार्गों से गुलाल-अबीर पुष्पों की बौछारों के बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह का अभूतपूर्व जुलूस उल्लास, नृत्य और नारों के साथ मंथर गति से गुजर रहा था। जुलूस को अवाक होकर देख रहे एक बुजुर्ग ने जुलूस के गुजर जाने के बाद पसीना पोंछते और कपड़े झाड़ते हुए कहा, "हमहूं तो ऐसन माहौल ७७ के बाद देख रहे हैं।" जुलूस में उत्साह से उन्मत्त युवकों की टोली गला फाड़-फाड़ कर नारे लगा रही थी: "राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है... तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।" यह जश्न दूसरे दिन रविवार को भी जारी रहा और जो लाउडस्पीकर १४ जून की शाम को मौन हो गये थे, उन पर फिर से फिल्मी गाने गूंजने लगे।

चुनौती : जैसा कि होना था, राजा ने जीत के बाद घोषणा की, "राजीव गांधी ने कहा था कि किसी व्यक्ति (अमिताभ बच्चन) के बजाय कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा जाये। अब मैं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत गया हूं, इसलिए राजीव गांधी तुरंत इस्तीफा दें।" स्वयं राजा का काफी दिनों से मौन कवि-मन पुन: मुखरित हुआ और उन्होंने कहा, "अब तो यह स्पष्ट है, राजीव गांधी भ्रष्ट हैं।"

यद्यपि राजीव गांधी उपचुनाव के नतीजों से संतुष्ट हैं और देश की राजनीति के निर्णायक प्रांत उत्तर प्रदेश की दोनों विधानसभाई (टांडा और छपरौली) और इलाहाबाद की लोकसभाई सीट गंवा देने के बाद भी उनको लगता है कि उनकी पार्टी के प्रति मतदाताओं की आस्था कम नहीं हुई है, लेकिन इन उपचुनावों के परिणामों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा-खासकर इलाहाबाद के उपचुनाव के परिणाम का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने इस उपचुनाव के महत्व पर टिप्पणी करते हुए 'माया' से कहा, "यह उपचुनाव नहीं जनादेश है। राजा ने रक्षा सौदों में दलाली को मुख्य मुद्दा बनाया था। राजीव गांधी ने बोफोर्स से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था। संयुक्त संसदीय समिति ने भी उनको पाक-साफ घोषित किया था, लेकिन राजा कह रहे थे कि नहीं—यह सब लीपापोती है। यही बात उन्होंने इस चुनाव में इलाहाबाद की जनता के सामने रखी और जनता ने उन्हें जिता कर उनके कथन पर मोहर लगा दी। दलाली का मुद्दा स्थानीय नहीं, देशव्यापी है। पिछले एक साल से पूरे देश में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष ने एक स्वर से राजा का साथ दिया है। ऐसी स्थिति में यह उपचुनाव आम उपचुनाव नहीं, बल्कि जनमतसंग्रह था जो राजा के पक्ष में गया है।"

लेकिन कांग्रेस के नेता इसे एक आम उपचुनाव मानते हैं। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और गुलाम नबी आजाद का कहना है, "उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसलिए ऐसे उपचुनावों में हार जीत कोई ज्यादा मायने नहीं रखती।" अपने इस्तीफे की जनमोर्चा द्वारा की गयी मांग का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "१६७८

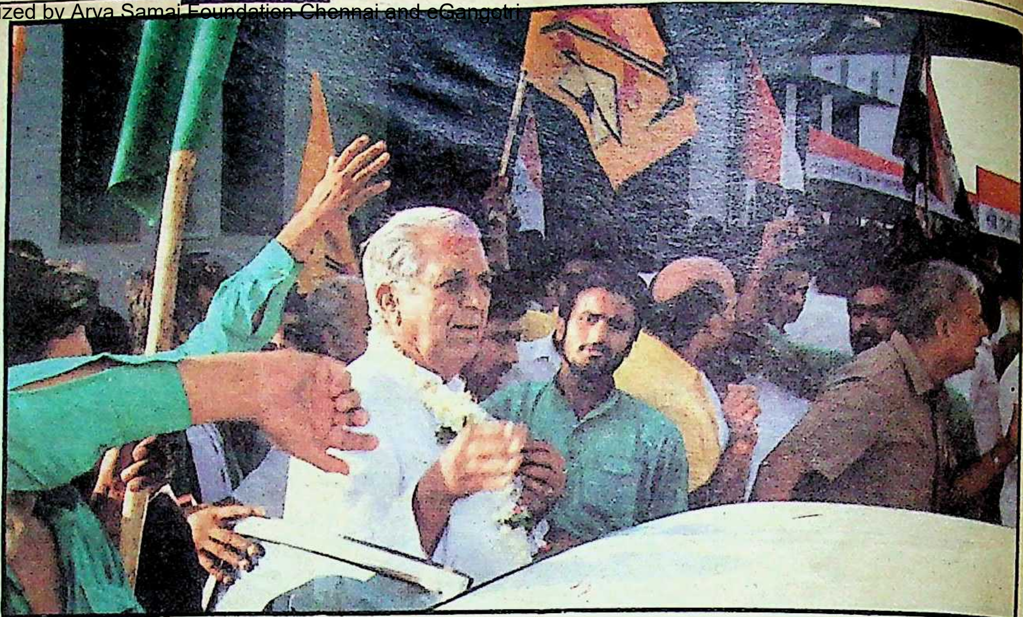

कांग्रेस को एक और मात : देवीलाल अभियान पर निकलते हुए

छाया : वसीमुल हक

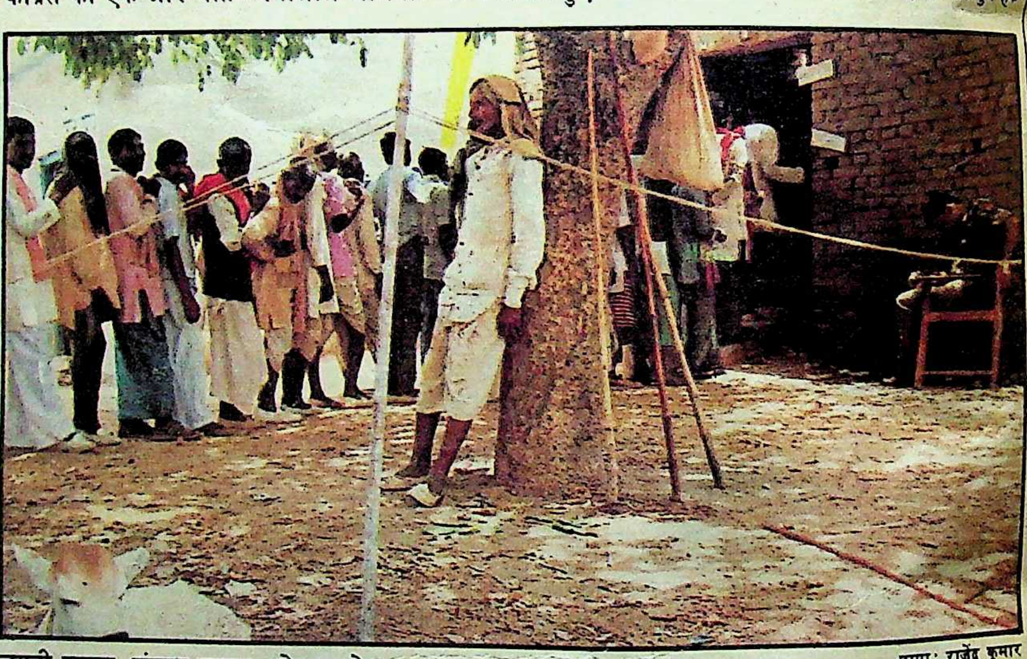

जगती जनता, ऊंघता बछड़ा, सोता दरोगा

छाया : राजेंद्र कुमार

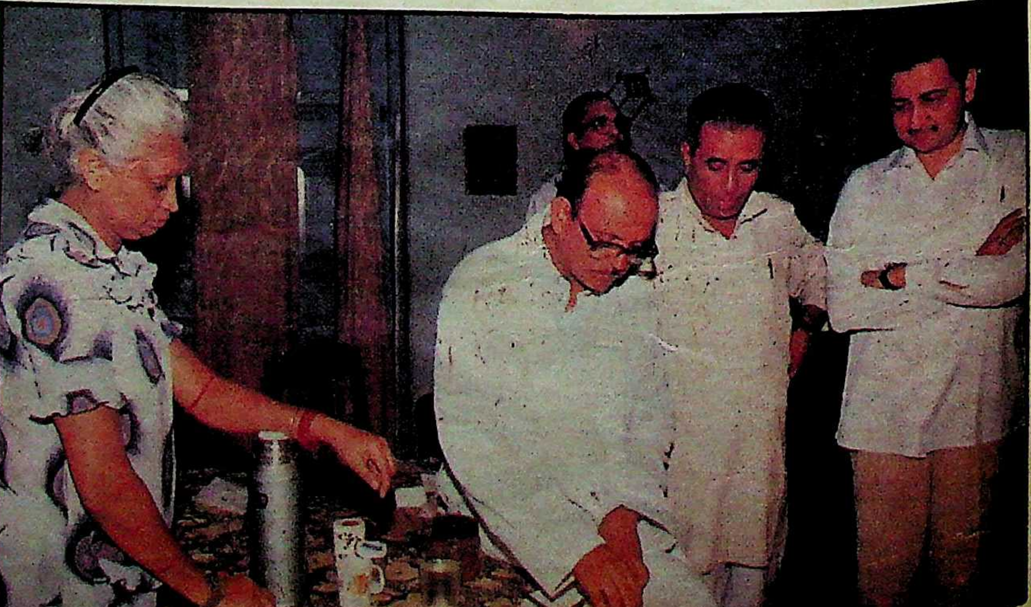

खाने की फुरसत कहां? : अभियान पर जाने के पूर्व नाश्ता करते राजा और नाश्ता करवाती रानी

छाया : मनमोहन शर्मा

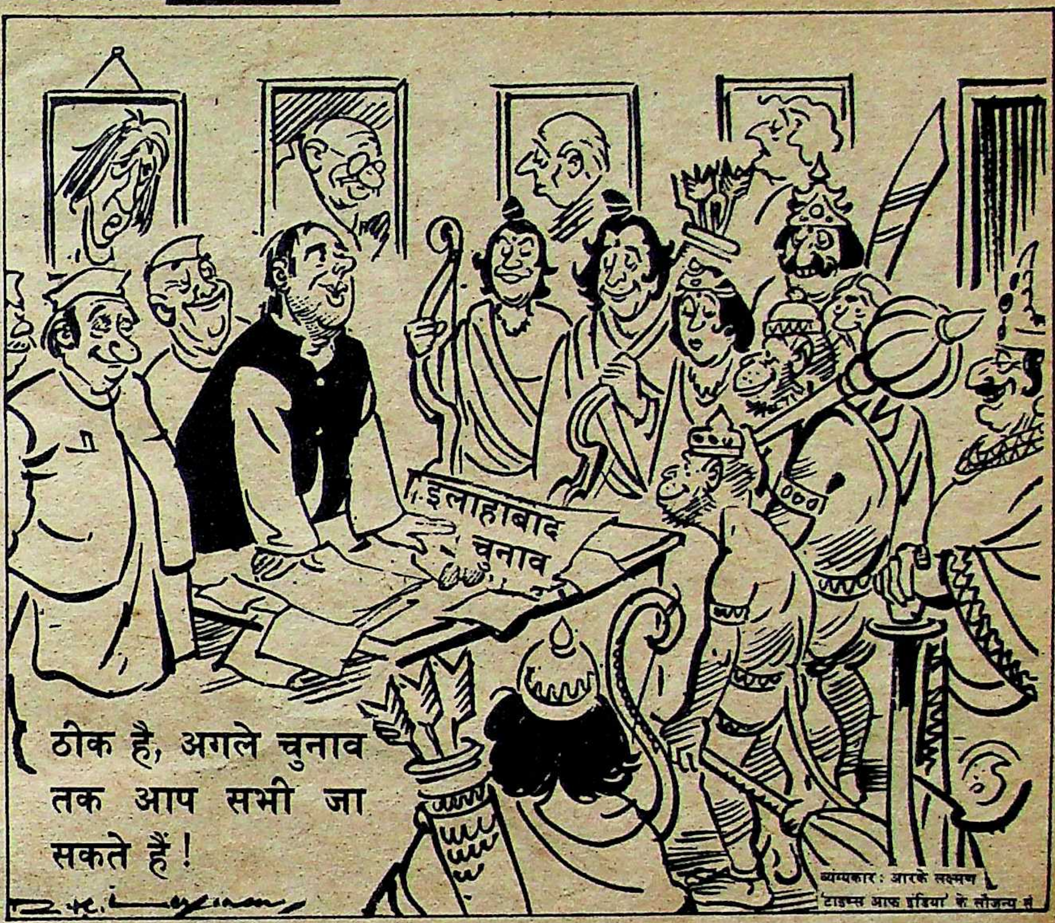
इलाहाबाद चुनाव
ठीक है, अगले चुनाव तक आप सभी जा सकते हैं!
R. K. Laxman

व्यंग्यकार: आरके लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य से

में जब रामनरेश यादव जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो आजमगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती मोहसिना किदवई जीती थीं और स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, तो गढ़वाल से विपक्षी नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जीते थे। उस समय जब किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब इस्तीफे की बात करना हास्यास्पद है।"

दोषारोपण: ऊपर से इस उपचुनाव को मामूली बताना आसान है, लेकिन इलाहाबाद की हार के बाद विभिन्न नेताओं द्वारा एक दूसरे पर दोषारोपण का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे साफ हो जाता है कि इंका नीचे तक हिल गयी है और नेता अपनी-अपनी गरदन बचाने की फिराक में लग गये हैं। इलाहाबाद चुनाव के 'सुपर इंचार्ज' बनकर आये रक्षा राज्य मंत्री संतोष मोहन देव ने अपनी १८ पृष्ठीय रिपोर्ट में हार के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'पदयात्रा' के दौरान किये गये वायदों को पूरा न करना, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और स्थानीय विधायकों की निष्क्रियता के कारण हार हुई है। इनमें गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित और विधायक द्वय सतीश जायसवाल (शहर द०) और रमाकांत मिश्र (बारा) का नाम गिनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा अरुण गोविल (राम) के खिलाफ बयान देने और पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी द्वारा एक जनसभा (अल्लापुर) में बाहुबल का उपयोग करने का मतदाताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कांग्रेस की हार का दोष स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी मढ़ा है, "वे मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बजाय वीपी सिंह, अरुण नेहरू और डा० संजय सिंह के प्रति ज्यादा वफादार थे।"

इसके विपरीत १७-१८ की रात लगभग एक बजे मतगणना पंडाल के बाहर अपने साथियों के साथ थके-हारे बैठे अशोक वाजपेयी ने 'माया' को बताया था, "पिछले तीन साल से अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद में कांग्रेस को चौपट कर दिया था। तब मैं अकेला शोर मचाता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उनके इस्तीफा देने के बाद से मैं कह रहा हूं कि यहां कुछ किया जाये, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेरा काम था शहर उत्तरी में कड़ी टक्कर देना और वह काम मैंने किया। लेकिन 'स्टूडेंट्स' के रवैये को भांपने में हमने गलती की। उन्होंने ही सारा पासा पलटा है।" वाजपेयी का यह भी मानना है कि संतोष मोहन देव जैसे केंद्र से आये लोगों ने चुनाव अभियान को बजाय सुसंचालित करने के मटियामेट किया है।

प्रत्याशी-चयन में देरी: मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और इंका प्रत्याशी सुनील शास्त्री ने हार के एक प्रमुख कारण की ओर संकेत किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस की हार का मूल कारण प्रत्याशी की पहले घोषणा न होना है। सभी जानते हैं कि २३ मई को अंतिम क्षणों तक यह प्रचार किया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन ही चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा गया कि प्रत्याशी का चयन मुख्यमंत्री और प्रदेश-इंका के अध्यक्ष महावीर प्रसाद करेंगे। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि यह सब दिखावा था (देखिए 'माया' जून प्रथम और द्वितीय)। सुनील शास्त्री मुख्यमंत्री की पसंद नहीं थे, आलाकमान की पसंद थे। मुख्यमंत्री की पसंद प्रांत के ग्रामीण विकास मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय थे। २३ मई को राजा को झूठा साबित करने के लिए कांग्रेस ने अंतिम क्षणों तक अमिताभ की रट लगाने और फिर सुनील शास्त्री को 'बलि का बकरा बनाने' के पीछे जो रणनीति अपनायी थी, उसका खमियाजा स्वयं कांग्रेस को उठाना पड़ा।

अजीत सिंह,
अध्यक्ष, जनता पार्टी

उपचुनावों ने दिखा दिया है कि जनता कांग्रेसी शासन से पूरी तरह निराश हो चुकी है। जहां विपक्ष ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी खड़ा किया, वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश और गुजरात में खास तौर से ऐसा हुआ है। संयुक्त प्रत्याशियों की जीत से विपक्षी एकता में बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी तरफ इस पराजय से कांग्रेस में बिखराव की प्रक्रिया शुरू होगी।

स्वयं सुनील शास्त्री भी मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हैं कि उन्हें चुनाव-प्रचार के लिए मात्र २१ दिन का समय मिला। जाहिर है उनको ऐन मौके तक पता नहीं था कि उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में चुनाव-प्रचार के दौरान सुनील शास्त्री को देखकर एक प्राध्यापक ने बड़ी मौजूं टिप्पणी की थी, "रेस में घोड़े तो बहुत दौड़ते हैं, लेकिन 'विनिंग हार्स' (जीतने वाले) एक-दो होते हैं। मुझे नहीं लगता कि सुनील 'विनिंग हार्स' हैं।" बहरहाल सुनील शास्त्री तो 'निमित्त' मात्र थे, चुनाव तो सारी कांग्रेस लड़ रही थी। प्रादेशिक और केंद्रीय नेताओं की भीड़ में सुनील शास्त्री के ओझल हो जाने पर मजाकिया टिप्पणी स्वयं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने की, "यह ऐसी शादी है, जिसमें दूल्हे के अलावा हर बाराती दूल्हा है।" डेढ़ दर्जन केंद्रीय मंत्रियों, अनगिनत सांसदों और सारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहां होने से स्थिति कुछ ऐसी ही थी। नेताओं की भीड़ पर टिप्पणी करते हुए सर्किट हाउस में बिहार के एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद ने चुटकी ली थी, "सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है कि यहां सेनापति ही सेनापति हैं, लेकिन सिपाही कहीं दिखायी नहीं देते।"

कार्यकर्ता कहां गये?: यही वह अहम मुद्दा है, जिसे सुनील शास्त्री ने अब उठाया है। उन्होंने अपनी हार का एक कारण कांग्रेस की स्थानीय गुटबंदी को बताया है, जिसके कारण हालत यह हुई कि उनको "१६ जून को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले।" यही नजारा मतगणना के समय पेश आया। मतगणना के समय कांग्रेस के पास पर्याप्त काउंटिंग

एजेंट नहीं थे, जिससे मतगणना यथासमय शुरू नहीं की जा सकी। विडंबना की बात यह है कि इधर कांग्रेस-इ कार्यकर्ताओं के लिए तरस रही थी और उधर १७ जून को रात में दूरदर्शन परिचर्चा में गुलाम नबी आजाद शेखी बघार रहे थे कि कांग्रेस के पास कर्मठ, निष्ठावान और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की फौज है, जबकि राजा के पास भाड़े के कार्यकर्ता थे, जिन पर काफी धन खर्च हुआ। इस संदर्भ में दिल्ली के एक पत्रकार की टिप्पणी गौरतलब है, “सच पूछा जाये, तो राजा के कार्यकर्ता स्वयंसेवी थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता परजीवी।” इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “आप शाम को ‘ऐश महल’ में जाइये और राजा के कार्यकर्ताओं की हुलिया और उनकी मोटर साइकिलें देखिए, सब कुछ धूल में लथपथ मिलेगा। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देखिए, मजाल क्या सफेद बुर्राक कुरते-पायजामे पर जरा-सा भी दाग हो।” इस कथन में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह बात काफी हद तक ठीक है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ज्यादा जोर गाड़ी, पेट्रोल और पैसों पर था। इसकी पुष्टि के लिए तीन उदाहरण काफी हैं।

लाल कृष्ण आडवाणी,
अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी

चुनाव परिणाम कांग्रेस-इ में होने वाले विद्रोह को रोकने और कुचलने में मददगार होंगे। लेकिन इलाहाबाद के हादसे से उबर पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। राजस्थान में नाथूराम मिर्धा और कल्याण कालवी ने कांग्रेस-इ की बजाय भाजपा और भैरों सिंह शेखावत का विरोध किया, इसलिए वहां इंका की साख बच गयी। लेकिन मतदाताओं ने लोकदल की जमानत जब्त करा दी। चुनाव परिणामों से यह भी साबित हो गया कि उत्तर में कम्युनिस्टों का कोई प्रभाव नहीं है तथा बंगाल में भी उसका जनाधार उखड़ रहा है।

मेनका गांधी,
महासचिव जनता पार्टी

हमें उम्मीद थी कि जहां विपक्ष एकजुट है, वहां हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। चुनाव परिणामों से साबित हो गया कि यदि विपक्ष एक जुट रहे, तो सत्तारूढ़ दल कहीं भी टिक नहीं पायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
सांसद, जपा

उप चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए भारी धक्का ही नहीं, एक अपशुकन भी है। किंतु जनता पार्टी के लिए यह एक प्रोत्साहन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार काफी हद तक खतम हो चुका है। पाली में विपक्ष की हार मेरे लिए आश्चर्यजनक है।

९ जून को सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पेट्रोल डीजल की पर्चियों के लिए कार्यकर्ताओं में मारामारी हुई। पर्ची काटनेवाले इंचार्ज के खिलाफ नारे लगे और भवन के शीशे तोड़ डाले गये।

एक रात सर्किट हाउस में ग्रामीण विकास मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय और बिहार के सांसद डीपी यादव कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे कि बिहार का एक बदहवास कांग्रेसी कार्यकर्ता आया और अतिशुद्ध हिंदी में ‘अस्वस्थ वाहन और रुग्ण चालक’ की तीमारदारी तथा कार के किराये की मांग करते हुए उसने कहा कि मैं केंद्रीय कार्यालय में जाता हू, तो कहा जाता है कि ‘श्री गोपीनाथ दीक्षितजी से मिलो’, वहां जाता हूं, तो आदेश होता है कि ‘श्री श्याम सूरत उपाध्यायजी के पास जाऊं, आप ही बताइये मैं क्या करूं? वह महाशय बिहार के एक सांसद के कार्यकर्ता थे। डीपी यादव ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, “अरे चार दिन का किराया ज्यादा-से-ज्यादा ३०० रुपए के हिसाब से १२०० रुपए होता है, क्या एक सांसद इतने पैसे अपनी जेब से नहीं दे सकता? मेरे पास इस समय ७ रुपए बचे हैं, लेकिन कल मैं कहीं से इंतजाम कर दूंगा, अब आप जाइए आराम कीजिए।”

लेकिन मुस्लिम वोट नहीं मिले: मुस्लिम क्षेत्र में आजाद

तीसरा उदाहरण १६ जून की एक घटना है। जिस समय जनमोर्चा के कार्यकर्ता भूखे-प्यासे मतपेटियों से चिपके बैठे थे, उस समय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में दो महिलाएं १८९ रुपए हासिल करने के लिए झगड़ा कर रही थीं और कुछ लोग इस फिराक में थे कि यह झगड़ा निपटे, तो हम भी वसूली करें।

बहरहाल गुलाम नबी आजाद ने स्वयं १७ जून को प्रसारित दूरदर्शन परिचर्चा में कहा है कि उनकी पार्टी ४० साल से शासन में है, इसलिए उसके पास पैसा है और वह खर्च कर सकती है। जाहिर है आज के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यह जान गये हैं कि पार्टी के पास ४० साल की कमाई है और उसमें हमारा भी हिस्सा है, इसलिए पार्टी के लिए काम नहीं, पार्टी से पैसे लेने पर उनका ज्यादा जोर है। एक वयोवृद्ध कांग्रेसी की यह बात काबिलेगौर है, “हमने भूखे-प्यासे रहकर कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन उस समय हमारे आदर्श महात्मा गांधी थे। लेकिन अब कांग्रेसी नेताओं को एयरकंडीशंड गाड़ी और एयरकंडीशंड कमरे चाहिए। जब इन चीजों के बिना हमारे नेता बाहर पांव नहीं निकालते, तो पार्टी के पांव उखड़ेंगे ही।” उक्त

हेमवती नंदन बहुगुणा,
अध्यक्ष लोकदल-ब

इस उपचुनाव से विपक्ष को भी चुनौती मिली है कि वह विकल्प तैयार करे। यह विकल्प व्यक्ति और नीति दोनों का होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में विपक्ष को सफलता जरूर नहीं मिली है। किंतु वहां भी उसका जनाधार काफी बढ़ा है। मसलन खरसिया में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मात्र आंठ हजार मतों से जीते हैं जबकि १९७७ में कांग्रेस ने यह सीट अट्ठाईस हजार मतों से जीती थी। इसी तरह, छपरौली में चौधरी चरण सिंह मात्र पांच हजार मतों से जीते थे, किंतु इस बार विपक्ष ने यह सीट बाईस हजार मतों से जीती है।

नेवादा में बूथ पर कब्जे के समय मोर्चेबंदी

वयोवृद्ध नेता ने मलीहाबाद के उपचुनाव का उदाहरण दिया, जिसे संजय मंच ने जीता था। उस चुनाव में काफी नेता ऐसे थे जो पैसा और गाड़ी लेकर बजाय क्षेत्र में जाने के लखनऊ में आकर होटलों में खान-पान करके दिन भर सोते थे तथा शाम को बाल बिखेर कर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आज हमने फलां-फलां गांव का दौरा किया तथा इतने वोट पक्के कर दिये। लेकिन अंत में वही हुआ जो इस उपचुनाव में हुआ।

इसी तरह का एक किस्सा इलाहाबाद में एक नामी 'कुक' ने सुनाया। यह 'कुक' लजीज सामिष व्यंजन बनाने के लिए मशहूर है। उसे चुनाव के समय अनुबंधित किया गया, यह कहकर कि उसे प्रतिदिन दो हजार लोगों के लिए खाना तैयार करना है। उसे वहां ले जाया गया, जिस जगह ज्यादा वोट प्राप्त करना इज्जत का सवाल था। जाने पर उसे पता चला कि वहां कांग्रेस के केवल दो-तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके लिए उसे खाना बनाना था। लौटकर उसने बताया कि उन महाशयों को वोटरों से ज्यादा इस बात की ज्यादा चिंता थी कि शाम को मुर्गा कहां से आयेगा और उसे कौन कैसे पकड़ेगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के सारे-के-सारे कार्यकर्त्ता पैसा खाऊ और मौज उड़ाऊ हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता जी लगाकर काम करना चाहते थे, उनको यह नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है और किससे आदेश लेने हैं, क्योंकि चुनाव प्रबंधक निरंतर बदल रहे थे। शुरू में गोपीनाथ दीक्षित चुनाव प्रंभारी थे, फिर सीताराम केसरी और गुलाम नबी आजाद ने सारी बागडोर संभाल ली। बाद में चुनाव संचालन में माहिर और मुख्यमंत्री के करीबी सांसद बलराम सिंह यादव भी इलाहाबाद में आ गये। इसके बाद चुनाव अभियान को चलते जब एक सप्ताह हो मया, तो रक्षा राज्यमंत्री संतोष मोहन देव सर्वेसर्वा हो कर आ गये। उन्होंने आते ही पिछली सारी रणनीति पलट डाली। एक कार्यकर्ता का कहना था, "पता नहीं उनका उद्देश्य चुनाव जिताना था या नहीं, लेकिन इलाहाबाद आये मंत्रियों-विधायकों को यह दिखाना उनका मकसद जरूर था कि जो वह कहते हैं, वही होता है। ऐसा लगता था जैसे वह नेता नहीं किसी फैक्टरी के मालिक हैं और बाकी नेता-कार्यकर्ता कर्मचारी हैं। वह चाहे जिसको झाड़ पिला सकते हैं। सुना है उन्होंने आते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री को ही झाड़ दिया था।"

स्वभाव और व्यवहार की बात अलग है, लेकिन शायद उनको यहां इसलिए भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा में दस साल से जमी वाममोर्चा सरकार को उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। लेकिन संतोष मोहन देव और अन्य ढेर सारे मंत्रियों-सांसदों के आ धमकने के बाद स्थानीय संजीदा कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित समझने लगते थे। उनको यह लगने लगा था कि चुनाव जीते, तो श्रेय इन महारथियों को मिलेगा नहीं तो कालिख का भांडा हमारे माथे पर फूटेगा। हुआ भी यही।

संगठन का अभाव : यह ठीक है कि प्रत्याशी की पहले घोषणा न करने, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का अभाव, एक-के-ऊपर-एक चुनाव-प्रबंधकों की परत और उनके परस्पर विरोधी निर्देशों के कारण कांग्रेस-इ का चुनाव अभियान सुचारु रूप से नहीं चल सका, लेकिन ये सब चुनाव के समय की परिस्थितियां थीं। ये स्थितियां इसलिए पैदा हुईं, क्योंकि चुनाव के पहले क़ांग्रेस ने संगठन स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस समिति काफी समय से निर्जीव पड़ी थी। प्रदेश समिति के अध्यक्ष

केपी उन्नीकृष्णन,
कांग्रेस-स नेता

इलाहाबाद का उपचुनाव स्पष्ट रूप से राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच संघर्ष था। वीपी सिंह की जीत भारतीय राजनीति में गुणात्मक बदलाव लायेगी। राजीव गांधी को तत्काल नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए।

पी उपेंद्र
सांसद, तेलुगु देशम

उपचुनावों के परिणामों से साफ जाहिर होता है कि राजीव गांधी के नेतृत्व और उनकी जनविरोधी नीतियों से जनता का विश्वास उड़ चुका है। इलाहाबाद में वीपी सिंह की जीत राजीव सरकार की कार्यशैली पर एक जनादेश है।

महाबीर प्रसाद वैसे ही कमजोर नेता हैं, इस पर उन्हें केंद्र में रेल उपमंत्री बना दिया गया। फिर सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। इलाहाबाद शहर कांग्रेस के अध्यक्ष का निधन पिछले दिसंबर में हुआ था, तब से अब तक वह पद खाली हैं। जब संगठन के स्तर पर यह हाल है, तो कार्यकर्ता कहां से आयेंगे और उनमें प्रतिबद्धता कैसे पैदा होगी? सेवादल और युवक कांग्रेस जैसे संगठन हैं, लेकिन इनमें भी सेवादल ही थोड़ा सक्रिय है और उसकी भी भूमिका सीमित है। यों इन चुनावों में ये दोनों संगठन लगे थे, लेकिन दीवारों पर नारे लिखने और 'ग्रीन ब्रिगेड' की नकल पर मोटर साइकिल रैली आयोजित करने के अलावा शायद ही इनका कोई और उपयोग किया गया हो।

चुनावी मुद्दे: इन सब कमियों को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाये, तो भी कांग्रेस. के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, जिसके आधार पर वह इलाहाबाद के मतदाताओं से वोट मांग सकती थी। कांग्रेस ने तीन आधारों पर इलाहाबाद की जनता से वोट मांगे: सुनील शास्त्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, राजा झूठे, गद्दार और विश्वासघाती हैं और इलाहाबाद के विकास की कुंजी कांग्रेस के ही पास है। लेकिन ये तीनों मुद्दे बेअसर साबित हुए। इसमें कोई शक नहीं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के प्रति जनता के मन में श्रद्धा है। लेकिन जनता के इन सवालों का कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं था: क्या स्वयं कांग्रेस के मन में स्वर्गीय शास्त्री के प्रति श्रद्धा है? यदि श्रद्धा थी, तो इसी चुनाव में वह क्यों याद आये, पहले उनके नाम पर क्या किया? फिर यह भी किसी से छिपा नहीं था कि वीपी सिंह व्यक्तिगत तौर पर शास्त्रीजी के प्रति कांग्रेस से ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। कांग्रेस का दूसरा मुद्दा था कि राजा झूठे और गद्दार हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को भूल गयी कि वह पिछले एक साल से राजा को जयचंद और विभीषण कहती आ रही है, लेकिन फिर भी राजा के पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है। जाहिर है चरित्रहनन पर आधारित पोस्टरों, नारों और गानों का जनता पर कोई अच्छा असर नहीं होना था, और वही हुआ। 'इलाहाबाद के बहादुरगंज क्षेत्र में एक ६५ वर्षीय दूकानदार से जब पूछा कि राजा को रावण और जयचंद बताने वाले पोस्टरों को देखकर आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने छूटते ही कहा, "यह लुच्चई और बेहयाई है, कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता।" लेकिन कांग्रेस ने इन पोस्टरों पर इतना जोर दे रखा था कि कहते हैं इसकी मानिटरिंग प्रधानमंत्री आवास से हो रही थी। राजा के चरित्रहनन के लिए 'हर तरह से लैस' एक दस्ता अमेठी से आया था, जिसका नेतृत्व अमेठी के विवादास्पद पत्रकार जगदीश पीयूष कर रहे थे।

कांग्रेस के पास तीसरा तीर था विकास का। मुख्यमंत्री ने खुले आम कहा कि मैंने ८० करोड़ रुपए इलाहाबाद के विकास के लिए मंजूर किये हैं। यदि सुनील शास्त्री को नहीं जिताया, तो यह विकास रुक जायेगा। लेकिन जनता को अमिताभ बच्चन के अपूर्ण हवाई वायदों की याद थी, इसलिए मुख्यमंत्री का यह प्रलोभन बेअसर रहा। अब तो यह प्रलोभन स्वयं सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है। जीतने के बाद राजा ने घोषित किया है कि मंत्रियों के लिए इलाहाबाद 'निषिद्ध क्षेत्र' है। जब भी वे आयेंगे उनका घेराव किया जायेगा, और कहा जायेगा—पहले ८० करोड़ लाओ, फिर शहर में आओ। सबसे हास्यास्पद तो सरकार की हैंड पंप लगवाने की चाल रही। ऐन चुनाव के मौके पर जगह-जगह हैंड पंप लगवाने का काम शुरू हुआ। अल्लापुर के एक पानवाले ने फब्ती कसी, "भैया हम जानत हैं, ये कुंभ मेले के लिए लग रहे हैं। लेकिन कुंभ के पहले ही ये बेकार हो जायेंगे, क्योंकि जल्दी-जल्दी में रोपे जा रहे हैं।"

जनाक्रोश: देखा जाये, तो कांग्रेस के हर हथियार के खाली जाने का मूल कारण था जनाक्रोश

केसरीजी चिरपरिचित मुद्रा में

ऐसे-ऐसे दिग्गज पहुंचे

इलाहाबाद के उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह और सुनील शास्त्री के पक्ष में जितने महारथी मैदान में उतरे, उतने आजादी के बाद किसी चुनाव में नहीं उतरे। ऐसा लगता था मानो देश और प्रांतों की एक मात्र राजधानी इलाहाबाद हो। इस चुनावी महाकुंभ में पक्ष और विपक्ष के जो महारथी पहुंचे, उनकी सूची इस प्रकार हैं:

पक्ष

मंत्री

१. नारायण दत्त तिवारी
२. एचकेएल भगत
३. बूटा सिंह
४. वसंत साठे
५. दिनेश सिंह
६. मोती लाल वोरा
७. संतोष मोहन देव
८. प्रियरंजन दासमुंशी
९. अजित पांजा
१०. श्याम लाल यादव
११. मोहसिना किदवई
१२. एचआर भारद्वाज
१३. बिंदेश्वरी दुबे
१४. एलपी शाही
१५. माधव राव सिंधिया
१६. महाबीर प्रसाद
१७. राजेंद्री वाजपेयी
१८. डूमर लाल बैठा
१९. एमएल फोतेदार
२०. कृष्ण कुमार
२१. शीला दीक्षित
२२. हरिकृष्ण शास्त्री

वरिष्ठ नेता

१. कमलापति त्रिपाठी

पार्टी पदाधिकारी

१. सीताराम केसरी
२. गुलाम नबी आजाद
३. शीला कौल
४. आस्कर फर्नांडीस
५. जगन्नाथ पहाड़िया

सांसद

१. डीपी यादव
२. कपिल वर्मा
३. कल्पनाथ राय
४. शिवप्रताप मिश्र उर्फ बाबा
५. सलीम शेरवानी
६. अमीन अंसारी
७. श्रीपति मिश्र
८. बलराम सिंह यादव
९. जगन्नाथ प्रसाद
१०. जितेंद्र प्रसाद
११. पीएन सुकुल
१२. तरुण कांति घोष
१३. बीएल शैलेश
१४. केके तिवारी
१५. ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री

१. अर्जुन सिंह
२. वीरभद्र सिंह
३. शिवचरण माथुर
४. वीर बहादुर सिंह और उनके लगभग सारे मंत्री

विपक्ष

१. देवीलाल (मुख्यमंत्री)
२. एनटीआर (मुख्यमंत्री)
३. हेगड़े (मुख्यमंत्री)
४. अजीत सिंह (जनता अध्यक्ष)
५. हेमवती नंदन बहुगुणा (लोकदल-ब अध्यक्ष)
६. चंद्रशेखर
७. अटल बिहारी वाजपेयी
८. विजया राजे सिंधिया
९. राजेश्वर राव (भाकपा महासचिव)
१०. समर मुखर्जी
११. ईएमएस नंबूदिरी पाद (माकपा महासचिव)
१२. केपी उन्नीकृष्णन (सांसद)
१३. मानवेंद्र सिंह (सांसद)
१४. मुफ्ती मोहम्मद सईद (सांसद)
१५. रामधन (सांसद)
१६. मधु दंडवते (सांसद)
१७. एम रघुपति (मंत्री कर्नाटक)
१८. जीवराज पांडियन (युवा जनमोर्चा तमिलनाडु)
१९. जयपाल रेड्डी (आंध्र प्रदेश, जनता सांसद)
२०. पी उपेंद्र (सांसद, तेलुगुदेशम)
२१. बीसी शुक्ल (सांसद)
२२. अरुण नेहरू (सांसद) ■

पहले पेट पूजा: कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री

और राजा का पिछले एक वर्ष से जनांकाक्षा का प्रतीक बनना। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि वह उसी तरह नयी पीढ़ी के दिल में बैठ गये, जैसे १९८४ में राजीव गांधी और अमिताभ (इलाहाबाद में) बैठे थे। यही नयी पीढ़ी राजा की जीत का खास कारण बनी है। इलाहाबाद के बैरहना क्षेत्र में दूध का कारोबार करने वाले युवा अनिल चौरसिया ने कहा, "मैं जनमोर्चा के कार्यकर्ताओं को फ्री खिला-पिला रहा हूं। मैंने पिछली दफा जैसे अमिताभ को जिताने के लिए काम किया था, वैसे ही अब राजा को जिताने के लिए काम कर रहा हूं।" एमटेक के छात्र अमरेंदु अल्लापुर के हैजा हस्पताल के पोलिंग सेंटर पर कार्यरत थे। उनसे पूछा कि मतदान कैसा हो रहा है? उन्होंने कहा, "जहां-जहां स्टूडेंट हैं, वहां-वहां भारी मतदान हो रहा है।" कारण पूछा, तो उन्होंने बताया, "स्टूडेंट वोट डालते हैं और डलवाते हैं, वैसे ही जैसे १९८४ में अमिताभ बच्चन के समय में हुआ था।" उन्होंने अमिताभ और वीपी सिंह की तुलना करते हुए कहा, "उस समय अमिताभ का ग्लैमर था और इस समय राजा हमारी आशा के प्रतीक हैं।" छात्रों में इस जोश के साथ दो छात्र नेताओं—विवि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी और नरेंद्र पाण्डे की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई से जन्मा गुस्सा भी था। छात्रों के इस जोश ने कहीं-कहीं कानून की सीमाओं का भी उल्लंघन किया है। एक छात्र को यह कहते हुए सुना गया, "मैंने अकेले २३ वोट दिये हैं, अब भी राजा हारते हैं, तो फिर उनका भाग्य।" शायद इसी आधार पर कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। संतोष मोहन देव ने तो पूरे आंकड़े देते हुए कहा है कि ३५ प्रतिशत सही मतदान हुआ है और १५ प्रतिशत धांधली हुई है। शुक्र है कि इसके बावजूद वह इतना मानते हैं कि "ईमानदारी से राजा ४०,००० मतों से जीते हैं।" लेकिन धांधली की केवल दो घटनाएं सामने आयी हैं और उन दोनों में ही कांग्रेस का हाथ बताया गया हैं।

एक घटना करछना के नेवादा मतदान केंद्र की है और दूसरी बारा में सतपुड़ा (उत्तर-दक्षिणी) के दो मतदान केंद्रों की। नेवादा में तो बाकायदा गोली चली और जनमोर्चा-समर्थक बरेली के जनता विधायक नरेंद्र पाल सिंह घायल हुए। आरोप है कि इस घटना में वे लोग शामिल थे, जिनको चुनाव के ऐन मौके पर एनएसए हटा कर छोड़ा गया था। सतपुड़ा में स्वयं अरुण नेहरू ने धांधली पकड़ी। वहां चुनाव के पहले ही पंजे पर मोहर लगा कर पेटियों में मत पत्र ठूंस दिये गये थे। नतीजतन वहां दुबारा मतदान हुआ।

युवा पीढ़ी के अटूट समर्थन के अलावा राजा को आम जनता के भरपूर मत इसलिए मिले, क्योंकि वह बाहर के नेता नहीं, बल्कि इलाहाबाद के हैं। पहली दफा लोगों को लगा कि अपना आदमी इलाहाबाद से लड़ रहा है। वह भी ऐसा आदमी, जिसका सारे देश में डंका पिट रहा है। यों तो राजा पहले भी यहां से दो बार लड़ चुके हैं। एक बार १९७७ में हार चुके हैं और दूसरी बार १९८० में जीत चुके हैं। लेकिन तब उनकी छवि एक ऐसे दब्बू व्यक्ति की थी जो जनहित के बजाय नेताहित को तरजीह देता था। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि उनमें ठाकुरों जैसा स्वाभिमान नहीं है। लेकिन जब से उन्होंने सत्ता को चुनौती दी है, सारे विपक्ष का विश्वास हासिल किया है और धनशक्ति के बजाय जनशक्ति का नारा दिया है, तब से उनकी छवि सारे देश में एक हिम्मती नेता की बनी है, जिसका लाभ उनको यहां मिला है। यही कारण है कि कांशी राम के जातिवाद और कांग्रेस-इ के सारे प्रलोभनों-तिकड़मों को नजरअंदाज करके हर जाति और धर्म के लोगों ने उन्हें भारी मतों से जिताया है। इसीलिए वह कहते हैं, "मैं नहीं जीता, यहां जनता जीती है।"

—माया टीम

लोगों ने अपनी भावना यों व्यक्त की!

चुनाव के बाद माया की टीम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सर्वे करके यह जानना चाहा कि मतदाताओं ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों चुना और सुनील शास्त्री तथा कांशीराम को क्यों हराया? इस सर्वे के दौरान हमें निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं मिली हैं:

"कांग्रेस की धांधली से सब उबियाय गये रहेन, ओइसे राजा अकेले लड़तेन तो मुश्किल रहा।" *—आटा चक्की मालिक नवन*

"विपक्ष की मजबूती के लिए राजा को वोट दिया गया। एक चुनाव जीत कर क्या हो सकता है। फिर भी राजा सिर्फ अपने आधे चुनावी वादे पूरा करें। असली काम देश को देखें।" *—चक्की वाले गोविंद लाल*

"सुनील को हम कैसे वोट देते? उनके भाई भी चुनाव जीते थे। फिर कभी झांकने नहीं आये।" *—दुकानदार मुन्नूलाल जायसवाल*

"राजा के खिलाफ कांग्रेस ने गलत ढंग से प्रचार किया। राजीव को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजा को प्रधानमंत्री बना दिया जाये।" *—होटलवाले किशनलाल*

"हिंदुस्तान भेड़िया धसान है। जिधर की हवा बहती है, सब उधर ही भागते हैं। दलाली ली, तो हम का करी, हम गरीब की कौन सोचता है?" *—मकरी*

"राजा साहब पूरे ईमानदार हैं। वरना भरी थाली में लात मार कर क्यों आते? नोट तो उधर थे। इधर क्या था? अकेले भी बहुत कुछ करेंगे।" *—घूरपुर बाजार के यूनुस भाई पत्रकार*

जब जनता को पता लगा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी सरकार का मुखिया स्वयं लिप्त है, तो जनता खुद सड़क पर निकल आयी। वीपी सिंह का चुनाव जनता ने स्वयं लड़ा। ***—नरेश सहगल, सीएवी इंटर कालेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता***

विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मजबूत विपक्ष देने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। ***—आनंद शुक्ला***

वीपी सिंह की साफ-सुथरी छवि तथा कांग्रेसियों से विश्वास उठ जाने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह जीते। करोड़ों रुपयों का अपव्यय चुनाव में होता है, इसलिए मध्यावधि चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं। जनाक्रोश मुख्य मुद्दा है कांग्रेस की हार का। ***—अनुराग सिंह, शोध छात्र, इलाहाबाद विवि दर्शन विभाग***

राजीव गांधी से अधिक मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का आक्रोश था, इसलिए संयुक्त विपक्षी मोर्चा के उम्मीदवार राजा साहब की ईमानदार छवि पर लोगों ने उन्हें अपना मत दिया। ***—मुकेश, फोटोग्राफर***

वीपी सिंह की जीत का सबसे बड़ा कारण वीर बहादुर सिंह, सीताराम केसरी एवं गुलाम नबी आजाद का बड़बोलापन एवं गुंडों को मीसा से छोड़ देना रहा है। ***—सुश्री नंदनी भारद्वाज***

वीपी सिंह ने इस चुनाव में वे सारे हथकण्डे अपनाये, जिससे कि कांग्रेसियों को मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने साम, दाम, दण्ड एवं भेद सभी का सहारा लिया। ***—कु० अनामिका***

न तो वीपी सिंह सीआईए के एजेंट सिद्ध हुए हैं और न ही गद्दार। उन्होंने गद्दारों का भण्डाफोड़ किया है। ***—अखिलेश श्रीवास्तव***

संयोजन: हर्षवर्धन कुलश्रेष्ठ, मीनूरानी दुबे

चुनाव-रणनीति

मगर राजा नहीं फंसे

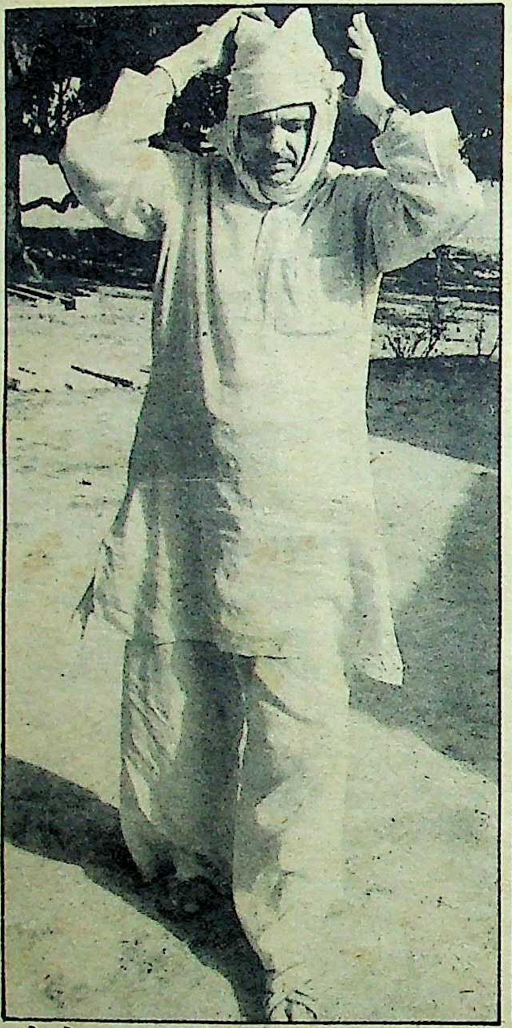

कांग्रेस से एक कदम आगे : राजा

अगर कांग्रेस के रणनीतिज्ञ गुलाम नबी आजाद, सीताराम केसरी, वीर बहादुर सिंह की बात सत्य मानी जाये, तो यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस राजा को एक चक्रव्यूह में फसाना चाहती थी। २४ मई को लगता था कि यह रणनीति सफल होने जा रही है। क़रीब-करीब १५ मार्च से राजा की रणनीति और चुनाव की पूरी तैयारी अमिताभ बच्चन को अपना प्रतिद्वंद्वी मान कर हुई थी। इलाहाबाद के मतदाता के सामने राजा ने एक ही मुद्दा रखा था कि बच्चन के जरिये राजीव गांधी ने दलाली खायी है और वह बच्चन को इसलिए हराना चाहते हैं, क्योंकि वह ऐसे तोते हैं, जिसमें राजीव गांधी की राजनीतिक जान है। कांग्रेस ने एकाएक यह तोता ही गायब कर दिया। सुनील शास्त्री के खड़े होने के बाद राजा एक प्रकार से निहत्थें हो गये। अब यह कहा जाता है कि चौबीस मंई को आजाद ने राजा को इसलिए चुनौती दी, जिससे कि राजा भाग न पायें। यहां तक कांग्रेस की रणनीति सफल हो गयी।

चार-पांच दिन राजा के पास कुछ कहने के लिए नहीं रहा और उधर कांग्रेस को यह मौका मिल गया कि वह राजा को झूठा कह सके और यह साबित कर सके कि राजा थूक कर चाटते हैं। वह केवल अमिताभ के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन उनके बिना खड़े हुए भी चुनाव लड़ रहे हैं।

यहीं से कांग्रेस की दूसरे दौर की रणनीति शुरू होती है। फिल्मी धुनों पर गाने तो बजाये जा ही रहे थे, दिल्ली में टनों कागज पर राजा के चरित्र-हनन के लिए तरह-तरह के पोस्टर भी तैयार करवाये गये, जिनको इलाहाबाद और गांव-गांव में लगाया गया। इनमें किसी में उन्हें रावण के रूप में चित्रित किया गया, तो किसी में कृष्ण को धोखा देने वाला अर्जुन कहा गया। यहां तक कि मेजा रोड पोलिंग बूथ जिस जगह पर था, वहीं सामने एक पोस्टर लगा था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर के नीचे उनके पुत्र सुनील शास्त्री की तस्वीर छपी थी। उसी पोस्टर पर ऊपर जयचंद का चित्र था और उसमें नीचे लिखा था, 'जयचंद के चालीसवें वंशज विश्वनाथ प्रताप सिंह' और फिर सिंह का चित्र छपा था। इसके पीछे इरादा यह था कि राजा को हर तरह से झूठा, धोखेबाज, बेईमान और गद्दार कह कर मतदाताओं के सामने बदनाम कर दिया जाये।

सुनील शास्त्री के खिलाफ इस किस्म का कोई अभियान राजा नहीं चला सकते थे। साथ ही मुख्य विपक्षी नेताओं की जो राजा के पक्ष में प्रचार करने इलाहाबाद आ रहे थे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और राजा के प्रति उनके पहले के मतभेदों का प्रचार किया गया। जैसे कि हेमवती नंदन बहुगुणा से आठ सवाल पोस्टरों के जरिये पूछे गये, जिनके जरिये यह दिखाना था कि बहुगुणा ने पहले राजा को एक बेईमान, भ्रष्ट और भूमिचोर साबित करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद जब बहुगुणा राजा के समर्थन में आने वाले थे, तो यह भी तैयारी हुई कि बहुगुणा के व्यक्तिगत चरित्र पर भी कीचड़ उछाला जाये। लेकिन क्योंकि बहुगुणा कुछ समय के लिए ही इलाहाबाद आये थे, इसलिए इसे अंजाम नहीं दिया गया। इस तरह से रणनीति का दूसरा दौर पूरा हुआ।

पहले राजा को पूरी तरह से बदनाम किया गया, उसके बाद उनके समर्थक विपक्षी नेताओं के, राजा के साथ पहले के मतभेदों के गड़े मुर्दे उखाड़े गये, जिससे कि यह प्रचार हो सके कि विपक्षियों का मेल सिद्धांतहीन है और उनका नापाक गठबंधन है।

इसके बाद तीसरे दौर में दो तरह की तैयारियां हुईं। पहली, उन पुरानी घटनाओं को खोद कर निकाला गया जो कि राजा के मुख्यमंत्री-काल की थीं, जिससे कि मतदाताओं के खास समुदाय को उनसे अलग किया जा सके। जैसे कि यह कहा गया कि डाकू उन्मूलन अभियान के दौरान कई हजार यादवों को उन्होंने मरवा डाला। ईद के दिन मुरादाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया। यह प्रचार पोस्टरों-विज्ञापनों के अलावा कांग्रेसी नेताओं ने अपने भाषणों में भी किया।

एक तरफ तो इस तरीके से राजा के वोट तोड़ने का प्रयत्न हुआ, दूसरी तरफ सुनील शास्त्री के वोट बढ़ाने के लिए हर जाति और समुदाय के नेता बुलाये गये और उनको वे क्षेत्र और मोहल्ले सौंपे

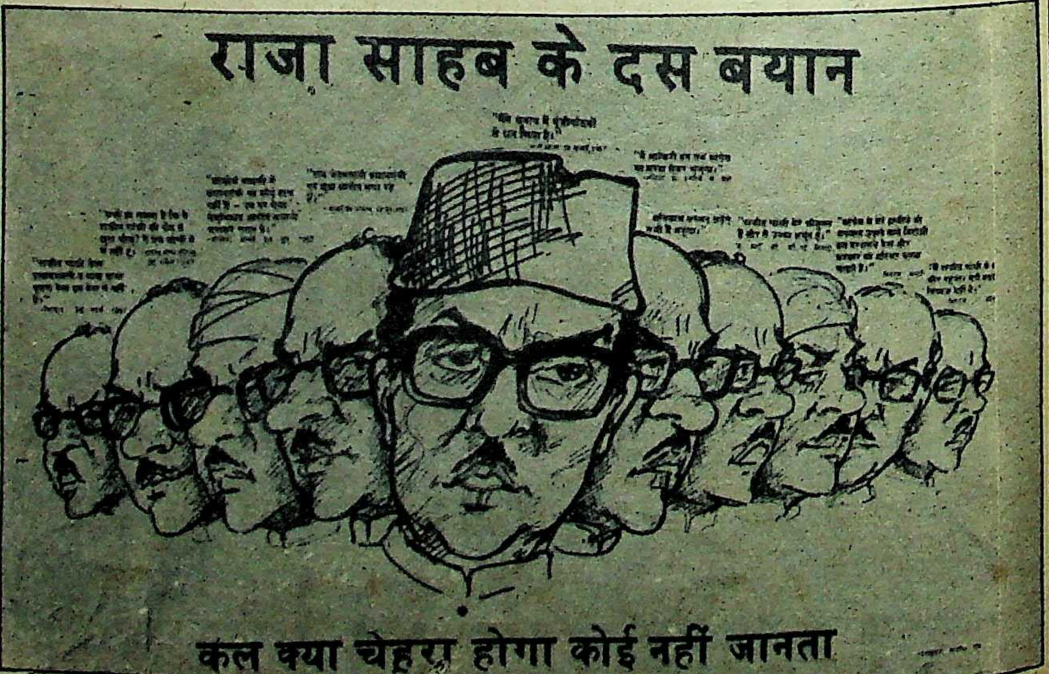
राजा साहब के दस बयान
कल क्या चेहरा होगा कोई नहीं जानता

मगर जनता ने 'रामायण' उजागर की : कांग्रेसी पोस्टर

गये, जहां उनकी जाति समुदाय के लोग थे। ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए नारायण दत्त तिवारी, मोतीलाल वोरा, कमलापति त्रिपाठी आदि बुलाये गये। यहां तक कि बंगालियों को फुसलाने के लिए प्रियरंजन दासमुंशी, अजीत पांजा और ममता बनर्जी को लाया गया, जो कि शायद ही पहले इलाहाबाद आये हों। उन्होंने मोहल्लों में अपनी-अपनी छोटी-छोटी बैठकें कीं।

बलराम सिंह यादव, डीपी यादव, श्यामलाल यादव जैसे नेताओं को यादव वोट पाने के लिए लाया गया। मुस्लिम समुदाय के वोट खींचने के लिए मोहसिना किदवई और सलीम शेरवानी को लगाया गया। सिखों के लिए बूटा सिंह को बुलाया गया। ठाकुरों के लिए दिनेश सिंह, अर्जुन आदि को प्रदेश के ठाकुर मंत्रियों, विधायकों के साथ लगाया गया। कायस्थों के लिए और कोई खास इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि सुनील शास्त्री स्वयं ही उस जाति के थे। कहा जाता है कि हर शाम को यह गणित बिठाया जाता था कि किस जाति के कितने वोट काबू में आ गये हैं। जाति के बाद धर्म की बारी थी। आखिर में एक तुरुप की तरह अरुण गोविल को लाया गया जो कि 'रामायण' में राम की भूमिका अदा कर रहे हैं।

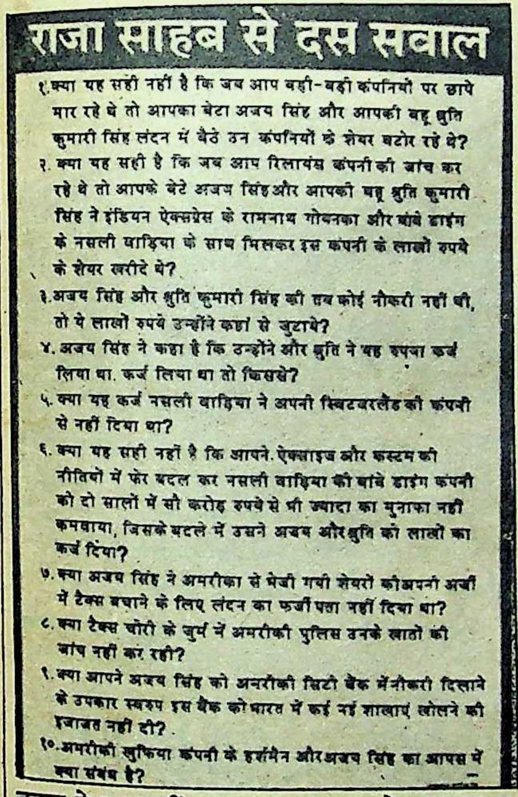

राजा साहब से दस सवाल

१. क्या यह सही नहीं है कि जब आप बड़ी-बड़ी कंपनियों पर छापे मार रहे थे तो आपका बेटा अजय सिंह और आपकी बहू श्रुति कुमारी सिंह लंदन में बैठे उन कंपनियों के शेयर बटोर रहे थे?

२. क्या यह सही है कि जब आप रिलायंस कंपनी की जांच कर रहे थे तो आपके बेटे अजय सिंह और आपकी बहू श्रुति कुमारी सिंह ने इंडियन ऐक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका और बांबे डाईंग के नसली वाड़िया के साथ मिलकर इस कंपनी के लाखों रुपये के शेयर खरीदे थे?

३. अजय सिंह और श्रुति कुमारी सिंह की जब कोई नौकरी नहीं थी, तो ये लाखों रुपये उन्होंने कहां से जुटाये?

४. अजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने और श्रुति ने यह रुपया कर्ज लिया था. कर्ज लिया था तो किससे?

५. क्या यह कर्ज नसली वाड़िया ने अपनी स्विटजरलैंड की कंपनी से नहीं दिया था?

६. क्या यह सही नहीं है कि आपने ऐक्साइज और कस्टम की नीतियों में फेर बदल कर नसली वाड़िया की बांबे डाईंग कंपनी को दो सालों में सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा का मुनाफा नहीं कमवाया, जिसके बदले में उसने अजय और श्रुति को लाखों का कर्ज दिया?

७. क्या अजय सिंह ने अमरीका से भेजी गयी शेयरों की अपनी अर्जी में टैक्स बचाने के लिए लंदन का फर्जी पता नहीं दिया था?

८. क्या टैक्स चोरी के जुर्म में अमरीकी पुलिस उनके खातों की जांच नहीं कर रही?

९. क्या आपने अजय सिंह को अमरीकी सिटी बैंक में नौकरी दिलाने के उपकार स्वरूप इस बैंक को भारत में कई नई शाखाएं खोलने की इजाजत नहीं दी?

१०. अमरीकी खुफिया कंपनी के हर्शमैन और अजय सिंह का आपस में क्या संबंध है?

जनता ने कहा-नहीं : राजा पर दस आरोप

आखिरी चाल यह थी कि प्रशासन को इस तरह से मोड़ा जाये कि कांग्रेस के पक्ष के मतदाता बंधे रह सकें। मसलन हरिजन आदि। दूसरी ओर राजा के पक्ष वाले थोड़ा भयभीत महसूस करें। जून १६ के दो-तीन दिन पहले से यह हवा बही कि हिंसा का खतरा है। इससे यह उम्मीद की जाती थी कि मतदान का प्रतिशत कम होगा और कांग्रेस अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर ज्यादा ला सकेगी और जरूरत पड़ी, तो हेराफेरी भी कर सकेगी। इस सबके लिए सरकारी तंत्र को ठीक किया गया। बहुत से तिपहियों, मैटाडोर वाहनों का इंतजाम किया गया। केवल बनारस से ही ढाई सौ रुपए प्रतिदिन के भाड़े पर ४५ तिपहिये लाये गये। कांग्रेस में जो आपसी मतभेद था, उसको भी दबाये रखने के लिए आजाद, केसरी और संतोष मोहन देव को बराबर इलाहाबाद में रखा गया। प्रचार के बंद होने के दो दिन पहले भाषणों के जरिये यह बात भी फैला दी गयी कि बिना कांग्रेस को वोट दिये सरकार से कोई उम्मीद न की जाये, जिससे कि व्यापारियों को प्रभावित किया जा सके।

इस सब रणनीति में जाति-धर्म को खूब उछाला गया और समाजवाद को ताक पर रख दिया गया। कांग्रेस के जितने सिद्धांत हैं, उन सबको भुलाकर निम्न और संकीर्णता के स्तर पर चुनाव अभियान को ले आया गया। फिर भी सफलता नहीं मिली। बदनाम भी हुए और मात भी हुई। जो गड्ढा राजा के लिए खोदा था, उसी में स्वयं कांग्रेस के सभी योद्धा जा गिरे।

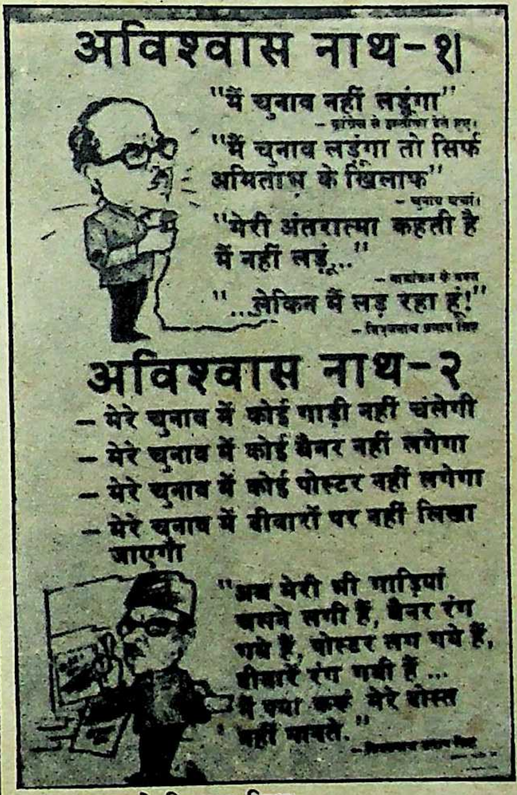

अविश्वास नाथ-१

"मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा"

"मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ अमिताभ के खिलाफ"

"मेरी अंतरात्मा कहती है मैं नहीं लड़ूं..."

"...लेकिन मैं लड़ रहा हूं!"

अविश्वास नाथ-२

- मेरे चुनाव में कोई गाड़ी नहीं चलेगी
- मेरे चुनाव में कोई बैनर नहीं लगेगा
- मेरे चुनाव में कोई पोस्टर नहीं लगेगा
- मेरे चुनाव में दीवारों पर नहीं लिखा जाएगा

"अब मेरी भी गाड़ियां चलने लगी हैं, बैनर टंग गये हैं, पोस्टर लग गये हैं, दीवारें रंग गयी हैं ... मैं क्या करूं मेरे दोस्त नहीं मानते."

मगर जनता ने विश्वास किया

वीपी सिंह : अब ऐसा लगता है कि राजा की सबसे सफल रणनीति यह थी कि कांग्रेस की हर चाल से एक कदम आगे चला जाये। राजा की सफलता का यही मूल कारण है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मूर्खता का प्रदर्शन करके कांग्रेस को मूर्ख बनाया। २३ मई की शाम को जबकि उनकी अमिताभ बच्चन वाली रणनीति बिलकुल धराशायी हो गयी थी, तो उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्येय—बच्चन को भगाने का—पूरा हो गया। 'मेरी तो विजय हो गयी', कहकर उन्होंने अपने चुनाव से हटने के इरादे का ऐलान कर दिया।

दूसरे दिन शाम को आजाद की चुनौती को बहाना बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चार-पांच दिन अपने अभियान को मंद रखा। हालांकि गांव में मोटर साइकिल पर लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर मिलते रहे। इस बीच समस्त विपक्षी नेताओं ने उनसे लड़ने का आग्रह किया। विपक्ष के उस आग्रह के कारण कांग्रेस का यह आरोप धूमिल हो गया कि राजा अपनी जबान के पक्के नहीं हैं। मगर राजा की सबसे बड़ी चाल जिसने कि कांग्रेस के हर दांव को काट दिया, वह थी युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके लिए उन्होंने मुद्दों पर आधारित अभियान शुरू किया और अपील की कि देश को दलालों से बचाने के लिए और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नयी पीढ़ी आगे आये। इलाहाबाद का नवयुवक खुद तो उत्साहित हुआ ही, मगर उसको तब और जोश मिला जब मद्रास, हरियाणा, बिहार, कोयंबटूर, महाराष्ट्र के हमउम्र युवकों की टोलियां राजा का चुनाव-कार्य करने पहुंचने लगीं। २५ नवयुवक जीवराज पांडियन (तमिलनाडु) लेकर आये और दो छात्र अपने खर्च से गुजरात के कच्छ जिले से ३ जून को इलाहाबाद पहुंचे। ऐसे युवकों के समर्थन से राजा फिर से इस चुनाव को मुद्दों पर आधारित करने में सफल हुए।

अमिताभ के न रहने और सुनील शास्त्री के खिलाफ कुछ भी न कह पाने के कारण उन्होंने चुनाव को सीधे-सीधे अपने और 'भ्रष्ट' कांग्रेस के बीच युद्ध का रूप दे दिया। जून के पहले हफ्ते से यह लड़ाई जन और धन के बीच मोड़ दी गयी। जब यह बात फैली कि स्थानीय प्रशासन की मदद से धांधली होगी, तो राजा ने मोटर साइकिल पर चढ़कर यह अभियान चलाया कि उन्होंने जनता की मदद से वोट तो इकट्ठा कर लिये, पर अब जनता को इन वोटों को लुटने से भी बचाना है। इसी के साथ-साथ राजा ने चुनाव स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच की लड़ाई बना दी। राजा ने कहा कि ५००० गुण्डे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और तमाम जेलों से उन लोगों को छोड़ दिया गया है जो यहां के गांवों पर अत्याचार करते रहे हैं। इससे जनता के मन में सरकार के प्रति इतनी नफरत हो गयी और राजा के प्रति इतना लगाव पैदा हो गया कि जब अरुण गोविल यहां आये, तो उनका जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, क्योंकि तब तक यह लड़ाई धर्म-जाति के दायरे से बाहर निकल चुकी थी।

उसके पहले राजा ने जून ११ को अटल बिहारी वाजपेयी, एनटीआर, देवीलाल जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं की पीडी टंडन पार्क में ऐतिहासिक सभा करके दो तरह की सफलता पा ली थी—पहली, एनटीआर (जिनको गांव में भी घुमाया गया) की धार्मिक अपील को भुनाकर अरुण गोविल की धार्मिक अपील कम कर दी थी और दूसरी तरफ १५ दिन की कांग्रेस की मेहनत कि विपक्ष सिद्धांतहीन हैं, धूल में मिला दी थी। सिरसा बाजार में १६ जून को एक रिक्शेवाले तक ने कहा, "भैया अरुण गोविल को हम देखने गये थे, सुनने नहीं। मगर अटल बिहारी को हम सुनने गये थे, देखने नहीं। जो आदमी अपने कान से सुनता है, उसी को मानता है।"

एक और चाल जिसने राजा को विजय श्री

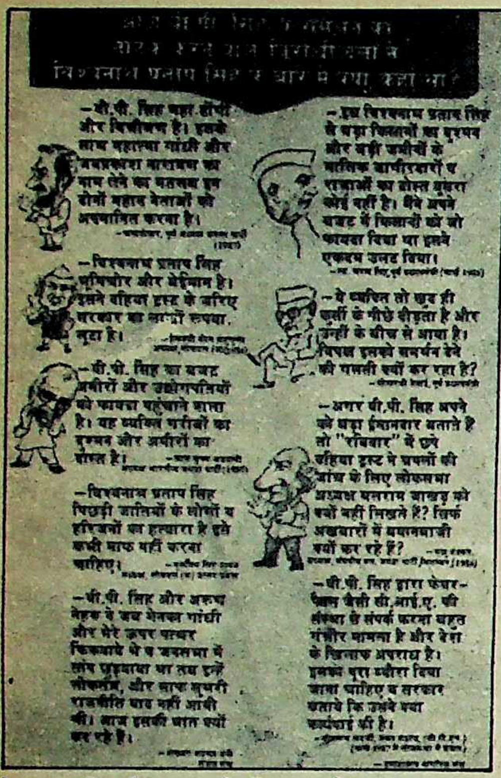

बेअसर: विपक्षी एकता के खिलाफ पोस्टर

दिलायी, वह थी जनता में ऐसी लहर पैदा कर दी कि वह जैसे खुद चुनाव लड़ रही है, ताकि मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो सके। यहां पर भी जात-पांत की कांग्रेसी रणनीति विफल हुई। एक तिलकधारी ५० वर्षीय पंडित बहुत उत्तेजित होकर मेजा रोड बाजार में दो मैटाडोर भरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जून १६ को १२ बजे लड़ रहे थे। उन्हें आशंका थी कि ये कार्यकर्ता बूथों पर कब्जा करने आये हैं। सही बात यह है कि राजा ने धांधली का आतंक इतना फैलाया था कि क्षेत्र भर के मतदाता सक्रिय हो गये और पुलिस तथा बीएसएफ के नौजवान बिलकुल सशंकित हो गये। कोरांव में १२ वर्ष के एक किशोर ने उत्तेजित होकर कहा कि हम लोगों ने बक्सों में ऐसे निशान डाले हैं कि अगर कांग्रेसियों ने बक्से बदले, तो उनका भंडाफोड़ हो जायेगा। १६ जून की शाम तक इतनी उत्तेजना फैली हुई थी कि किसी कांग्रेसी की हिम्मत कोई गड़बड़ी करने की नहीं रह गयी थी और दो दिन पहले से गांवों में कम-से-कम यह तय हो चुका था कि राजा जीत चुके हैं।

जात की चाल, चरित्रहनन की चाल और विपक्ष को सिद्धांतहीन बताने के पैंतरे राजा ने खतम कर दिये। पहले तो राजा ने यह साबित कर दिया कि वह इलाहाबाद की जमीन से जुड़े हैं। दूसरे, इलाहाबाद में ऐसी राजनीतिक चेतना है कि अब उसी के जरिये देश को 'राजीव के दलालों' से बचाया जा सकता है। अंतिम दिन कांग्रेसी विदेशी बन गये थे और राजा अपने घर का एक सदस्य और घर का सदस्य अच्छा हो या बुरा, उसे बाहरी से बचाना परिवार के अन्य सदस्यों का धर्म होता है। यही बात राजा की जीत का आधार बनी।

कांशीराम: बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कांशीराम यह बात भली भांति जानते थे कि इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव जीतना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु वह यह भी जानते थे कि अपनी पार्टी के प्रचार और देश भर के हरिजनों-पिछड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस ऐतिहासिक चुनाव से अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है।

इसके लिए कांशीराम ने भी वीपी सिंह की तरह बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। करीब छह माह पहले उन्होंने इलाहाबाद के सेंट जोजफ कालेज ग्राउंड में अपनी पार्टी और उससे संबद्ध विभिन्न संगठनों की एक विशाल रैली एवं सभा आयोजित की थी। उस रैली एवं सभा में उनके समर्थकों की उपस्थिति देखकर ही राजनीतिक प्रेक्षक कहने लगे थे कि भारतीय राजनीति में एक तीसरी शक्ति उभर रही है जो शीघ्र ही सभी राजनीतिक दलों को धूल-धूसरित कर देगी। हालांकि इसके पूर्व उनकी पार्टी ने बिजनौर और हरिद्वार के संसदीय उपचुनावों में भी अपनी शक्ति से न केवल कांग्रेस को, बल्कि विपक्ष को भी आश्चर्यचकित कर दिया था।

जात की चाल, चरित्रहनन की चाल और विपक्ष को सिद्धांतहीन बताने के पैंतरे राजा ने खतम कर दिये। पहले तो राजा ने यह साबित कर दिया कि वह इलाहाबाद की जमीन से जुड़े हैं। दूसरे, इलाहाबाद में ऐसी राजनीतिक चेतना है कि अब उसी के जरिये देश को 'राजीव के दलालों' से बचाया जा सकता है। अंतिम दिन कांग्रेसी विदेशी बन गये थे और राजा अपने घर का एक सदस्य और यही बात राजा की जीत का आधार बनी।

किसको कितने मत मिले?

वीपी सिंह को २०३१६७, सुनील शास्त्री को ९२१९४ और कांशीराम को ६९५१७ वोट मिले। इन तीनों के अलावा शेष ६५ प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गयीं। इनमें से अधिसंख्य की प्राप्त मत संख्या दो या तीन अंकों में ही थी। ८३६८३७ मतदाताओं के इस क्षेत्र में कुल ३९१९५७ मत पड़े। ५५९३ मत अवैध रहे। लगभग सात हजार वोट विवादास्पद होने के कारण गिने नहीं गये।

१९८४ के महानिर्वाचन में जहां हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज महारथी के बिरुद्ध कांग्रेस की इज्जत को अमिताभ बच्चन ने बरकरार रखा था, वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस को २४.६ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इलाहाबाद के सम्पूर्ण चुनावी इतिहास में कांग्रेस को प्राप्त यह सबसे कम मत प्रतिशत है। १९७७ की जनता आंधी में जब जनेश्वर मिश्र जीते थे, कांग्रेस की ओर से विश्वनाथ प्रताप सिंह ही पराजित उम्मीदवार थे। उन्होंने तब भी ३०.४७ प्रतिशत मत बटोर लिये थे। इलाहाबाद लोकसभा तथा छपरौली और टांडा विधान सभाओं के उपचुनाव में गिरी हुई साख के इस दौर में कांग्रेस को २८.६ प्रतिशत वोट मिले, जबकि तीनों विजेता प्रतिपक्षी उम्मीदवारों का प्राप्त मत प्रतिशत ५२.८ है।

कांशीराम ने इलाहाबाद में चुनाव-प्रचार के दौरान हर जगह यही कहा कि इस देश में हमारी आबादी ७५ प्रतिशत है। अल्पसंख्यकों को शामिल करके हमारी आबादी ८५ प्रतिशत हो जाती है, फिर भी हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। ये १५ प्रतिशत सवर्ण हम पर शासन कर रहे हैं। हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हम ८५ प्रतिशत होकर भी असहाय और मूकदर्शक बने हुए हैं। हमें यह स्थिति बदलनी होगी।

कांशीराम तो नहीं उनके अन्य साथी यहां तक कहते सुने गये कि इन सवर्णों की बहू-बेंटियां हमारे घरों में पानी भरेंगी, बरतन मांजेंगी और पांव दाबेंगी। हम अपने पर हुए सभी अत्याचारों का बदला चुन-चुनकर लेंगे।

आरक्षण की आलोचना करते हुए कांशीराम कहते रहे कि यह हमारे वास्तविक अधिकारों से वंचित रखने की सुनियोजित एवं कुटिल साजिश है। 'हम' ८५ प्रतिशत हैं और हमें आरक्षण दिया जाता है १५ प्रतिशत। वास्तव में आरक्षण तो इन सवर्णों को दिया जाना चाहिए जो कि आबादी के कुल १५ प्रतिशत हैं। हम अपने शासन में सवर्णों को १५ प्रतिशत आरक्षण देंगे। हालांकि कांशीराम के पास (यानी बीएसपी के पास) धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपने सदस्यों से सर्वाधिक एवं नियमित चंदा उसे ही मिलता है। फिर भी वह अपने को शोषित-हरिजनों से जोड़ने के लिए उनसे वोट के साथ नोट भी मांगते थे। इस तरह वह मतदाताओं के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करते थे। कांशीराम केवल हरिजनों, पिछड़ों और निम्नवर्गीय मुसलमानों, ईसाइयों की बस्ती में ही गये। कांशीराम ने पोस्टरों-बैनरों पर पैसा फूंकने के बजाय 'वाल राइटिंग' पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नगर एवं ग्रामीण इलाकों में हरिजन बस्तियों में प्रत्येक झोंपड़ी एवं मकान पर उन्होंने चुनाव चिह्न और नारा लिखवाने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने एक लाख स्थानों पर अपना चुनाव चिह्न 'हाथी' बनवाने का दावा किया है।

जहां कांग्रेस और वीपी सिंह प्रेस से निरंतर संपर्क बनाये हुए थे, वहीं कांशीराम प्रेस को दुत्कारते फिर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रेस उनको रहस्यमय मानकर उनके पीछे-पीछे लगा रहा और वह भरपूर प्रचार पाते रहे। यद्यपि कांशीराम ६९,५१७ मत ही बटोर पाये, लेकिन उन्होंने जात-पांत का जो जहर घोला है, वह खतरनाक है।

—विजयदत्त

छाया: वसीमुल हक, मनमोहन शर्मा

साक्षात्कार/**विशवनाथ प्रताप सिंह**

यह प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला है

माया : ***चुनाव जीतने के बाद आपकी नजर में अब इलाहाबाद और दिल्ली के बीच कितना फासला है?***

वीपी सिंह : यह समझिए कि अब से आम चुनाव तक।

माया : ***यह कहा जाता है कि इस उपचुनाव में कोई लहर नहीं थी और इसे राजीव गांधी के खिलाफ जनादेश की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आप अपने चुनाव के परिणाम को किस रूप में देखते हैं?***

सिंह : कांग्रेस को मुगालता है और वह चाहती है कि यह बना रहे। उत्तर प्रदेश में तीन उपचुनाव हुए हैं और ये तीनों ही कांग्रेस ने हारे हैं। राजीव गांधी अपने घर (इलाहाबाद) में ही उपचुनाव हार गये हैं, जिसको उन्होंने प्रतिष्ठा का बिंदु बना रखा था। पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर देखिए—पूर्व में इलाहाबाद, पश्चिम में छपरौली और बीच में टांडा। इस प्रकार वह अपने गृह राज्य में पूरी तरह हार गये।

माया : ***जिन लोगों से आपने सहायता की अपील की थी, उनके अलावा आपको किन लोगों की सहायता मिली?***

सिंह : यहां के और देश के अन्य हिस्सों के लोगों ने भी सहायता की। खासकर विपक्ष ने, जिसने एक होकर काम किया। मेरे प्रति यहां के लोगों के व्यक्तिगत लगाव को मत भूलिए, क्योंकि इलाहाबाद मेरा घर है।

माया : ***लेकिन आप पर तो यह आरोप है कि आप इलाहाबाद से बाहर रहे हैं और आपने मांडा तक पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां पीने का पानी तक नहीं। फिर क्या कारण है कि लोगों ने आपका साथ दिया?***

सिंह : सवाल यह नहीं है कि किसी ने माडा के लिए क्या किया, बल्कि देश के लिए क्या किया? यही मुद्दा था। कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? वे ऊंचे लोगों के भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं, रक्षा सौदों में दलाली को संरक्षण दे रहे हैं। लोग यह नहीं पूछ रहे कि गांवों का क्या हो रहा है, वह पूछ रहे हैं कि देश के साथ क्या हुआ और इलाहाबाद के लोग हमेशा देश के साथ रहे हैं। राजीव गांधी अपने परिवार का इतिहास तक नहीं जानते।

माया : ***आपने लोगों से यह क्यों कहा है कि वे मंत्रियों का घेराव करें? क्या आप यह सोचते हैं कि लोगों को जो लाभ मिला है, वह अब नहीं मिलेगा?***

सिंह : नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया है। सिर्फ ८० करोड़ का वायदा था। कोई ठोस काम नहीं हुआ। यह एक थोथा आश्वासन था। लेकिन उन्होंने चुनाव के पहले जो वायदे किये हैं, उन्हें बाध्य करेंगे कि वे पूरा करें।

माया : ***आपका मतलब यह है कि आपको मत देकर लोगों ने देशभक्ति का परिचय दिया है और वे दौलत के लालच में नहीं फंसेंगे?***

सिंह : ऐसा नहीं है कि केवल इलाहाबाद के लोग ही ऐसे हैं, सारे देश के लोग ऐसे हैं। यह चीज राजीव गांधी नहीं समझते और कांग्रेस भी नहीं समझती।

माया : ***क्या आप सोंचते हैं कि इस चुनाव से वे कोई सबक लेंगे?***

सिंह : यदि वे सबक ही लेते, तो हालात ऐसे थोड़े ही होते?

माया : ***आप पर जो व्यक्तिगत आरोप लगाये गये कि आप जयचंद हैं, विभीषण हैं, आपको पोस्टरों में रावण के रूप में दिखाया गया। क्या आप सोचते हैं, लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा? आपने भी व्यक्तिगत आरोप लगाये कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं। क्या चुनाव-नतीजों का मतलब यह है कि जो कांग्रेस ने कहा, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और आपकी बातों को सच माना?***

सिंह : लोगों को सच की पहचान है। उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते।

माया : ***आपकी दृष्टि में आपके चुनावी मुद्दे कौन से थे?***

सिंह : भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था। राजीव गांधी की सरकार भी एक मुद्दा था। 'अब तो यह स्पष्ट है, राजीव गांधी भ्रष्ट हैं', 'राजीव गांधी होश में आओ, देश का पैसा देश में लाओ' आदि नारे उसी के प्रतीक हैं। उन्होंने इनका खंडन करने की कोशिश की। अब जनता ने अपना फैसला दे दिया है। पिछले एक साल से ऊंचे लोगों के भ्रष्टाचार पर बहस छिड़ी हुई है और मैंने इसे इलाहाबाद के लोगों को बताया, क्योंकि मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। मैंने सीधा राजीव गांधी पर आरोप लगाया और अब लोगों का निर्णय आ गया है कि मैं सही हूं और राजीव गांधी गलत हैं।

माया : ***चुनाव के दौरान मुद्दों के बजाय व्यक्तियों पर ज्यादा जोर दिया गया?***

सिंह : राजीव गांधी ने कहा था कि मुझे एक व्यक्ति यानी अमिताभ बच्चन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं एक व्यक्ति के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? लड़ाई नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से नीतियों और कार्यक्रमों पर फैसला देने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। दरअसल यह स्वयं प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार को एक मुद्दा बना कर इलाहाबाद के लोगों के सामने रखा था। वीपी सिंह राजीव गांधी के कार्यक्रम के खिलाफ लड़ा है।

माया : ***यह सही हो सकता है, लेकिन मात्र एक इलाहाबाद के उपचुनाव को इतना महत्व क्यों दिया जाये और उसे राजीव गांधी के खिलाफ जनादेश क्यों कहा जाये?***

सिंह : जब राजीव गांधी विदेश में थे, तो उन्होंने केवल इलाहाबाद का उल्लेख किया। यह भी कहा कि वह यहां जीत रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने केवल एक चुनाव पर दांव लगाया था, इसलिए हारने के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिएं।

माया : ***केंद्रीय और राज्यमंत्रियों की भीड़ को देखकर क्या कभी आपको हार जाने की आशंका हुई?***

सिंह : राजनीतिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि मालूम था कि मंत्रियों के सारे प्रयास जनता विफल कर देगी। लेकिन वे सारे हथकंडे अपनाने पर तुले थे, क्योंकि राजीव गांधी ने उन्हें हर कीमत पर चुनाव जीतने के लिए कहा था।

माया : ***इससे आपका मतलब?***

सिंह : अपराधियों को सक्रिय किया गया। मुख्यमंत्री उनसे मिले, उनके साथ खाना खाया—उदाहरण के लिए नैनी के मन्नीलाल। जो एनएसए (रासुका) के तहत फरार थे, उन्हें वापस लाया गया और वह मंत्रियों के साथ टहले। उनको बूथों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया।

माया : ***ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय पुलिस ने आपका पक्ष लिया।***

सिंह : मुझे बताया गया कि चुने हुए ५०-दारोगा दूसरी जगहों से लाये गये। कहा जाता है कि उन्हें १०-१० हजार रुपए देकर कहा गया कि वह फलां-फलां बूथों पर कब्जा करें।

माया : ***लेकिन प्रदेश के मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि १५ जून की मध्य रात्रि में धांधली करने के लिए जनमोर्चा ५००० गुंडे लाया था।***

सिंह : वह हमें हमारी धांधली की एक ही घटना बता दें।

—विजयदत्त

श्रीमती सीता सिंह

विश्वनाथ की शक्ति

भविष्य के प्रति आश्वस्त: सीता सिंह

पति देव जब तक सरकार में रहे, तब तक वह घर के अंदर एक साधारण पत्नी बनकर गृहस्थी संभालतीं और नाती-नतिनी के साथ हंसती-खेलती रहीं। सीता सिंह को एक ही बात खलती रही है, जिसे वह गाहे-बगाहे जाहिर भी करती रही हैं, "वह अकसर यहां से वहां जाते-आते रहते हैं, मगर कभी मुझे अपने साथ नहीं ले गये।"

जब वह वित्त मंत्री हो गये और महाराष्ट्र के पार्टी संबंधी मामलों के प्रभारी बना दिये गये, तब सीता देवी ने बड़ी ललक के साथ मन की बात रखी, "मुझे कम-से-कम एक बार बंबई ले चलकर घुमा दीजिए।" लेकिन मीठे स्वर में ही उन्होंने कह दिया, "यह मुझसे नहीं हो सकेगा।" जब सिंह साहब को वित्तमंत्री की हैसियत से हवाई जहाज की सुविधा मिली, तब सीता देवी को लगा कि अब मौका आया। वह खुशी से गदगद हो गयीं। मन-ही-मन कहा, "अब तो एक-आध बार इनके साथ जाने का अवसर मिलेगा ही।" तब तक न तो दीवालों पर भद्दी शिकायतें लिखी गयी थीं और न सिंह के अचानक हटने-हटाये जाने की कोई कचोटने वाली बात हुई थी।

शुरू में जब डइया ट्रस्ट का मामला उछाला गया और जमीन हड़पने का आरोप लगाया, तब सीता देवी का खून खौल उठा था, "बहुत गुस्सा आता था। झूठ फैलाकर बदनाम करना चाहते थे कुछ लोग।" लेकिन उन दिनों सीताजी यह कल्पना तक नहीं कर सकती थीं कि उनके पति पर किये जा रहे इन हमलों को राजीव गांधी की शह मिली हुई है, "ये हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में उनको इंदिराजी ने मौका दिया था—१९६८ में टिकट देकर।" इसके बाद सिंह ने अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह उन्हीं के (इंदिराजी के) हाथ में छोड़ दिया, "जितना पुराना साथ था और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, उसे देखते हुए यह सोचा ही नहीं जा सकता था कि राजीवजी को इनकी निष्ठा पर कोई शक होगा।" जब हालात ने सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, तब वह तिलमिला उठी थीं, "दुख तो हुआ कि राजीवजी के रहते ऐसे हालात पैदा हो गये। मगर गुस्सा ज्यादा आया।" वास्तव में वीपी सिंह ने जब इस्तीफा दे दिया, तब सीताजी ने राहत महसूस की, बेकार बकवास हो रहा था। अपने ही लोग बुरा-भला कह रहे थे। मुझे 'रिलीफ' मिला कि अब सारी गंदगी से मुक्ति मिल गयी।" इन्होंने अपने पति को इस्तीफा देने का अफसोस नहीं होने दिया, "हमने तो कहा कि अच्छा ही किया।"

इसके पांच साल पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना सीता देवी को खल गया था। लेकिन इस मामले में वह कुछ कर नहीं सकती थीं। तब की बात याद दिलाने पर वह कहती हैं, "हमें अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने अपना 'पर्सनल लेटरहेड' मांगा था, उसी वक्त हमें अंदाज हो गया था कि अब यह 'रिजाइन' करेंगे। इन्हें मना करने की हिम्मत मुझमें नही थी। बड़े सख्त दिखायी दे रहे थे थे।"

बहरहाल, सीता सिंह ने अपने पति से राजनीति पर कभी बातचीत नहीं की, "कभी अगर कोई बात की, तो फौरन डांट पड़ जाती है।" वह नारी सुलभ झेंप के साथ बताती हैं, "परिवार के लोगों में राजनीतिक बतकही की, एक तरह से, मनाही है।" शायद इसी वजह से, वीपी सिंह के राजनीतिक उतार-चढ़ाव से वह विचलित नहीं होतीं।

१८ जून की सुबह जब वीपी सिंह लोकसभा उपचुनाव में जीत के करीब पहुंच गये, तब अचानक सीता सिंह की तबीयत खराब हो गयी। वह बुखार में बिस्तर पर पड़ी थीं। तभी मांडा महल के हाते में पांच सौ लोगों ने जोर से नारा लगाया, 'जीत गये जीत गये' वीपी सिंह जीत गये!' यह नारा पहली मंजिल पर सीता सिंह के सोने के कमरे में गूंज उठा। लेकिन वह खुशी में बहकीं नहीं। उन्होंने संयत स्वर में कहा, "चाहे जो हो जायें या बनें...।"

"चुनाव प्रचार में आपकी भूमिका क्या रही?" इस सवाल के जवाब में वह बोलीं, "हम ४ अप्रैल से यहीं (इलाहाबाद में) हैं। मगर हमारा काम, जो लोग यहां घर में थे उनके लिए, खाना बनवाने और कुछ स्लोगन (नारे) लिखने तक सीमित था।" लेकिन वह चुनाव प्रचार करने कभी-कभी बाहर भी गयीं। "क्या आप इस बात से खुश हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह संसद सदस्य बन गये हैं?" "चाहे जो बन जायें, सब ठीक है मेरे लिए।"

उनकी न कोई खास ख्वाहिश है, न वह इस प्रश्न पर कोई टिप्पणी करने वाली हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है, "यह सवाल उनसे पूछिए।" वह कतई नहीं चाहतीं कि फिर भद्दगी चालू हो जाये, बुराई और आरोपों का दौर चले। इससे उनके दिल को ठेस लगती है।

सीता सिंह राजस्थान के उदयपुर स्थित देवगढ़ की लड़की हैं। कम उम्र में ही इनकी शादी हो गयी। इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि पतिदेव इतने मशहूर होंगे। उन दिनों की याद दिलाने पर वह कहती हैं, "हमने नाम ही नहीं सुना था इनका, देखना तो दूर था।"

जब वीपी सिंह रक्षामंत्रालय और कांग्रेस से हट गये, तब सीता देवी उनका काम अधिक करने लगीं। किंतु राजनीति का काम नहीं, सामान्य व्यवस्था का काम-मसलन दौरे की तैयारी, लोगों से मिलने-जुलने का कार्य आदि-आदि। सीता सिंह कहती हैं, "इस्तीफा देने के बाद तो ये बहुत कम घर पर रहे। बराबर घूमते रहे हैं। हम उनके आने-जाने का हिसाब रखते थे, जिससे कि फोन पर लोगों को बता सकें कि वह कब मिलेंगे।" वह मानती हैं कि इलाहाबाद में मिली सफलता जन समर्थन की देन है, और किसी चीज की नहीं। "तो क्या आप चाहती हैं कि आपके पतिदेव कुछ और हो जायें?" जवाब में सीता सिंह कहती हैं, "वह जो कुछ हो गये हैं, हम उतने से संतुष्ट हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं चाहते?"

"आपने अपने पति का बीस वर्षों का राजनीतिक जीवन देखा है। क्या आप कह सकती हैं कि राजनीतिक पुरुष आदर्श पति हो सकता है?"

"ना, एकदम नहीं।" दो टूक उत्तर है उनका।

उनकी बहन उत्साह के साथ कहती हैं कि ऐसा हो सकता है। किंतु सीता देवी के पास, साफ तौर पर, एक पत्नी की हैसियत से शिकायत करने के लिए भी कोई खास बात नहीं है। वास्तव में सीता देवी इस कहावत को सार्थक बनाती हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। वीपी सिंह की सफलता और ख्याति में सीता देवी का सबसे बड़ा योगदान उनकी मुसकराहट है। चाहे जो भी हालात हों, वह मुसकराती रहती हैं।

"क्या आप चाहती हैं कि वह प्रधानमंत्री हो जायें?"

"इनके एमपी होने से ही हम खुश हैं।" कहते-कहते ही वह मुसकराने लगती हैं। संभवत: यह मुसकान अपने पति के उज्ज्वल भविष्य के प्रति सीता सिंह की आस्था का द्योतक है।

—**विजय दत्त**

और ये ब्रिगेड

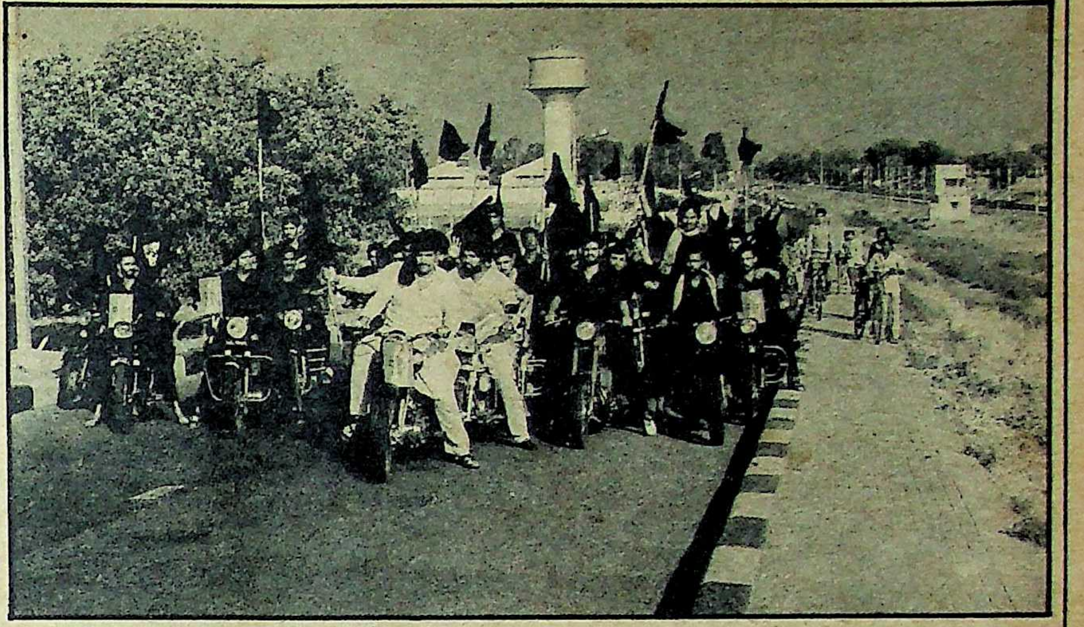

लोकदली सेना: वीपी के समर्थन में हरियाणा से आयी ग्रीन ब्रिगेड

इलाहाबाद लोकसभा का चुनाव कई दृष्टियों से चर्चा का विषय रहा। जहां सतरंगी बैनरों, पोस्टरों, बंदनवारों, तोरणद्वारों और नारों तथा गीतों से चुनावी युद्ध जीतने की हर उम्मीदवार ने अपने-अपने ढंग से कोशिश की, वहीं उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंची 'ब्रिगेडें' काफी चर्चित रहीं। एक ब्रिगेड के जवाब में दूसरी ब्रिगेड को तैयार किया जाता रहा। इलाहाबाद की सड़कों पर हरे रंग के कुर्ता-पाजामा, गुलाबी रंग का कुर्ता और सिर पर साफा, पीले रंग की कमीज या कुर्ता तथा तिरंगा सिर पर बांधे युवकों का दल जब निकलता, तो एक अनोखा नजारा सामने आता।

पर इन ब्रिगेडों में सबसे चर्चित और विवादास्पद ब्रिगेड रही—'ग्रीन ब्रिगेड'। ५ जून की शाम को मोटर साइकिल पर सवार 'ग्रीन ब्रिगेड' के दो सौ जवान जब इलाहाबाद पहुंचे, तो शहर में एक किस्म की सनसनी फैल गयी। यह ब्रिगेड हरियाणा से वीपी सिंह के चुनाव-प्रचार के लिए आयी थी। ६ जून को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल इलाहाबाद की सड़कों पर निकले, तो एक सौ मोटर साइकिलों पर सवार दो सौ जवानों का दल उनके आगे-पीछे चला। हालात ऐसे हुए कि 'ग्रीन ब्रिगेड' के बारे में तरह-तरह की चर्चाएं हवा में उछलने लगीं। ९ जून को बाकायदा एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता राज्यमंत्री श्याम लाल यादव ने आरोप लगाया, "हरियाणा से लाये गये 'ग्रीन ब्रिगेड' में वहां के पुलिस, होमगार्ड और सरकारी कर्मचारी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल गहरी हरी वर्दी में इन सरकारी कर्मचारियों को यहां लाकर आतंक पैदा करना चाहते हैं।" यादव ने उप्र के गृहमंत्री से इसकी जांच करवाने की मांग भी की।

यादव के इस बयान के बाद उप्र के गृहमंत्री ने बिना जांच-पड़ताल किये बयान दे दिया कि दूसरे राज्य की पुलिस बिना अनुमति के उप्र में नहीं आ सकती। ग्रीन ब्रिगेड को जांचने-परखने का गुप्त काम सरकार की ओर से शुरू भी हो गया।

उप्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री और केंद्रीय सरकार के मंत्री के इन आरोप भरे बयानों के जवाब में देवीलाल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके 'ग्रीन ब्रिगेड' से हिंसा की आशंका है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। देवीलाल ने इस आरोप को निराधार बताया कि उनकी 'ग्रीन ब्रिगेड' में हरियाणा की पुलिस और होमगार्ड के जवान तथा अराजक तत्व हैं। उन्होंने कहा कि हरी पोशाक में उनके युवा विधायक और युवा लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो चुनाव-प्रचार में मदद करने आये हैं। ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया हरियाणा में लोकदल विधायक सुरेंद्र सिंह और युवा लोकदल-ब की हरियाणा शाखा के अध्यक्ष जय प्रकाश ने भी चुनौती दी, "कोई सिद्ध करके दिखाये कि हम असामाजिक तत्व या पुलिस के लोग हैं। हम सबके पास परिचय पत्र हैं और हम जांच के लिए तैयार हैं।"

इस संवाददाता ने चुनाव कवरेज के दौरान ग्रीन ब्रिगेड के दो सौ जवानों को गांवों में पहुंचकर वीपी सिंह को जिताने की अपील करते देखा। वे ग्रामीणों से कहते थे कि हरियाणा में देवीलाल की सरकार आयी, तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, किसानों को हर समय बिजली मिलती है, बेरोजगारों को बेरोजगारी-भत्ता मिलता है, वृद्धों को पेंशन की सुविधा दी गयी है, व्यापारियों पर लगे अनाप-शनाप टैक्सों को हटा दिया गया है। यदि आप वीपी सिंह को जितायेंगे, तो विपक्ष इसे यहां लागू करवाने के लिए सरकार से लड़ेगा। १६ वर्ष से लेकर ६५ वर्ष तक के कार्यकर्ताओं वाली इस ब्रिगेड ने गांव-गांव में देवीलाल और वीपी सिंह का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसके अतिरिक्त ग्रीन ब्रिगेड के जवानों के आने के बाद इलाहाबाद के मतदाताओं में भी एक जोश पैदा हो गया कि अब कांग्रेसी बेईमानी नहीं कर पायेंगे।

'ग्रीन ब्रिगेड' से अभिभूत होकर तेलुगुदेशम के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटीआर भी पीतांबरधारी कार्यकर्ताओं के साथ इलाहाबाद की धरती पर उतरे। लगभग ५०० पीतांबरधारी लोगों ने घर-घर घूमकर टूटी-फूटी हिंदी में वीपी सिंह के लिए जनसमर्थन मांगने का काम शुरू किया, तो इसे नाम मिला 'यलो ब्रिगेड'। एनटीआर ने अपने 'यलो ब्रिगेड' के लिए कहा कि इसमें उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता हैं। यह राष्ट्र के लिए हमारा योगदान है।

'ग्रीन ब्रिगेड' और 'यलो ब्रिगेड' के बाद वीपी सिंह के स्थानीय समर्थकों ने 'पिंक ब्रिगेड' बना लिया। इसके लोग गुलाबी रंग का कुर्ता और सिर पर गुलाबी साफा बांधे चुनाव-प्रचार में लग गये।

ब्रिगेडों के इस युद्ध में जवाबी हमले के लिए उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस-इ ने 'तिरंगा दस्ता' का गठन किया, जिसमें पांच सौ सदस्यों को शामिल किया गया। इलाहाबाद की सड़कों पर बाकायदा स्कूटर-मोटर साइकिल पर इनका जत्था निकला। इस जत्थे के गठन पर जत्थे के एक प्रवक्ता ने कहा था कि ग्रीन ब्रिगेड के जवाब में तिरंगा दस्ता बना है। ग्रीन ब्रिगेड के लोगों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा किया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। लेकिन इलाहाबाद चुनाव के महा संग्राम में 'ग्रीन ब्रिगेड' पूरी तरह छायी रही।

—दिनेश दीनू

छाया: वसीमुल हक

दो तरफा चेतावनी

सब कुछ समाप्त हो चुका है। बाकी है, तो थोड़ा सा शोर और वह भी मद्धिम स्वर में। ऐसा प्रतीत होता है, अब तक हवा में व्याप्त कड़कती आवाजों को स्वेच्छाचारी मतदाताओं के अप्रत्याशित फैसले ने वज्रपात कर खामोश कर दिया है। १९७७ से लगातार भारतीय मतदाता ने दंड देने की जो ठानी हुई है, वह आज तक बरकरार है। ११ वर्ष पूर्व इसी के तहत उसने श्रीमती गांधी का बोरिया-बिस्तर बंधवा दिया था। और तब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जब तक उन्होंने अपने तौर-तरीकों में रद्दोबदल नहीं किया। तीन वर्ष पश्चात उनका तो खैरमकदम किया गया, किंतु लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर पानी फेरने वाली जनता पार्टी को दरवाजा दिखा दिया गया था। पिछले लगभग एक दशक से विपक्ष इंतजार में है कि कब वापसी के लिए उन मतदाताओं से कोई इशारा प्राप्त हो, जिन्होंने उसे वनवास दिया था। और वर्तमान उपचुनाव को संकेत माना जाये, तो ऐसा लगता है कि उसे अभी काफी समय और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि संकेत से लगता है कि यह समय इतना लंबा न हो जितना कि उसे डर है।

६५ लाख मतदाताओं की संख्या वैसे तो नगण्य है, किंतु फैसले सांकेतिक होकर भी महत्वपूर्ण हैं। जिन सात संसदीय सीटों के उपचुनाव हुए हैं, वे सभी शासक दल के पास थीं। अब तक प्राप्त नतीजों में वह ६ में से मात्र २ सीटों को बरकरार रख पायी है हरियाणा की जिस फरीदाबाद संसदीय सीट की मतगणना रोक दी गयी है, उसकी आशा करना भी इंका के लिए बेकार ही है। इस प्रकार यह कोई उपलब्धि नहीं कहलायेगी। दिग्गज विपक्षी नेता जिस विशेष लहर की बात कह रहे थे, सतह पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कहीं अता-पता नहीं था। किंतु यह निष्कर्ष भ्रामक है। लहर थी, और मजे की थी। जिस पार्टी ने ६ में से ४ सीटें खो दी हों और पांचवीं का भी खोने का अंदेशा हो, उसे अगले आम चुनावों से पूर्व अत्यधिक आत्मालोचन करना होगा। क्योंकि अगला चुनाव कहीं अधिक निर्णायक और उतना ही घातक होगा।

यह भी सही नहीं है, जैसा कि अनेक टिप्पणीकार कहते नजर आ रहे हैं कि मतदाता भ्रमित हैं, शायद उन राजनीतिज्ञों से भी अधिक दिग्भ्रमित हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं कि वे आ रहे हैं या जा रहे हैं। मतदाता सजा देने के 'मूड' में हैं। उन्होंने हर पार्टी पर कोड़े बरसाये हैं। मसलन इलाहाबाद में कांग्रेस पर, राजस्थान में विपक्ष पर और प० बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी पर, जहां बराबनी में उसका उम्मीदवार कांग्रेस से हार गया है। इलाहाबाद में केवल एक ही मुद्दा था—भ्रष्टाचार का और मतदाताओं ने बोफोर्स के हो-हल्ले को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला दिया है, जिसने नयी दिल्ली में अवश्य ही दहशत फैला दी होगी। राजस्थान में विपक्ष एकजुट होने में विफल रहा और उसे कीमत चुकानी पड़ी। वहां के लोकदल उम्मीदवार ने अपनी जमानत जब्त करा दी। यह सही है, किंतु प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते ठीक से नहीं चल पायी। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक गुट दूसरे गुट की टांग खींचने की कोशिश में लगा था।

गुजरात में इसके विपरीत जनता और भाजपा दोनों ने गर्मजोशी के साथ मोर्चा बनाया और कांग्रेस से लोकसभा और विधानसभा की एक-एक सीट जीत कर शासकदल के साथ तालमेल के पुराने नुस्खे को निरर्थक साबित कर दिया। यदि राजस्थान में लोकदल की इकाई, जिसे वहां की जनता पार्टी ने उकसाया और मदद पहुंचायी, ने गलत चाल न चली होती, तो पाली और खेतड़ी का नतीज़ा दूसरा ही होता। जैसा कि स्पष्ट है कि मतदाता ऐसे जुर्मों को माफ नहीं करते। वे गलती करनेवाली पार्टियों पर तीखा प्रहार करते हैं। खासकर विपक्ष पर, जिसकी जनता में यह छवि बनी हुई है कि ये सब आपस में ही कट मर रहे हैं और अपनी-अपनी बरबादी का कारण बने हुए हैं। मतदाताओं के मन में ऐसे लोगों के लिए कतई सहानुभूति नहीं। उन्होंने १९८० में उन्हें (विपक्ष को) बोरिया-बिस्तर सहित वापस भेज दिया था। अगले वर्ष मतदाता अपना यही रवैया दोहरा सकते हैं, यदि उनका (परस्पर संघर्षरत विपक्ष का) लड़ने-झगड़ने से पेट नहीं भरा।

एक मौका और: जिस एक अहम मुद्दे को अधिकांश राजनीतिक पर्यवेक्षक नजरंदाज कर रहे हैं, वह यह है कि १९८० के बाद से पहली बार मतदाता विपक्ष को एक मौका देने को तैयार हुआ है, बशर्ते विपक्ष एकजुट हो। ऐसा १९८४ में भी मुमकिन नहीं हुआ था। यह जरूर है कि तब हालात एकदम अलग थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की इलाहाबाद की जीत में जहां उनकी शिष्ट-शालीन और पाक-साफ छवि का हाथ था, वहीं यह तथ्य भी था कि वह समूचे विपक्ष का सहयोग पाने में सफल रहे थे। शायद इसीलिए विपक्ष ने इलाहाबाद में अपनी वे चालें नहीं चलीं, जैसा कि उसने राजस्थान में किया था। यदि उसकी (विपक्ष की) पांतों में दरार की हलकी झलक भी उजागर होती, तो उसने राजा को संगम में डुबो दिया होता। वीपी सिंह की पराजय हर रूप में अनर्थकारी होती। क्योंकि उस हालत में बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू के मुद्दों के बाद—जिससे वीपी सिंह सरकार और पार्टी से अलहदगी के लिए मजबूर हुए—तमाम घटनाओं पर वैधता की मुहर लग जाती। दरअसल पराजय खुद भ्रष्टाचार को वैध करार देकर उसे एक संस्थागत आधार प्रदान करती, जैसी कि कांग्रेस को उम्मीद थी। मतदाताओं ने यह चाल शुरू में ही भांप ली थी और उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया था। इलाहाबाद में गच्चा खाने के बाद कांग्रेसी बिना निगाहें नीची किये बोफोर्स के बारे में बात नहीं कर सकेंगे।

> मतदाताओं ने ऐलानिया कह दिया है कि शासक दल और विपक्ष दोनों की स्थिति अस्थायी है और वह यदि नहीं संभले, तो १९८९, अथवा जब भी अगले चुनाव हों, में उनकी हालत बिगड़ सकती है। यदि विपक्ष एकजुट हो सके और चंद्रशेखर जैसे बड़ी भूख वाले छोटे आदमी को उनकी औकात जता सके, तो वह दूसरे १९७७ की उम्मीद कर सकते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि यदि अमिताभ बच्चन खड़े होते; तो स्थिति क्या होती ? तीन साल पहले वह धुआंधार बहुमत से जीते थे। उन्हें ६८ प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसा अनुमान किया जाता है—यद्यपि ऐसे अनुमानों की सत्यता संदिग्ध है—कि दो तिहाई बहुमत अमिताभ ने अपनी निजी छवि से प्राप्त किया था और एक तिहाई पार्टी की वजह से। अगर ऐसा ही था, तो अमिताभ इस बार भी अपनी निजी छवि के बलबूते जीत सकते थे। लेकिन उनकी मौजूदगी भ्रष्टाचार के मुद्दे को और ज्यादा उभार देती और उनकी छवि को गहरा धक्का लगता।

किंतु कांग्रेससियों ने अपनी चालें ठीक नहीं चलीं। यह उनके हित में होता, यदि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को कम महत्व देते। किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और बोफोर्स और दिल्ली से जिसका दूर का नाता न होता। अर्थात कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसी ऐसे स्थानीय नागरिक को बनाती, जिसने इलाहाबाद की गलियों के बाहर कदम नहीं रखा हो और जिसे यह नहीं मालूम हो कि स्वीडिश मुद्रा क्रोनर की क्या कीमत है। किंतु जब कांग्रेसी जागे, तब बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में उन्होंने

कहना शुरू किया कि इलाहाबाद का उनके लिए बहुत महत्व नहीं है और दिल्ली सरकार पर इस चुनाव से कोई असर नहीं पड़ने वाला है—यहां तक कि लखनऊ सरकार पर भी नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि असर प्रभावशाली और दूरगामी होगा, क्योंकि वीपी सिंह अब ऐन संसद में आ गये हैं, जहां बोफोर्स की तोपें अगले चुनाव तक गरजेंगी और वह (वीपी सिंह) उसका संचालन करेंगे। और यही वह स्थिति है, जिसको कांग्रेसी होने नहीं देना चाहते थे और अब वह इससे अपना दामन नहीं बचा सकते हैं। उनकी सारी जोड़-तोड़ गलत साबित हुई। सच तो यह है कि बोफोर्स घोटाला जब से उभरा है, तब से उनकी एक-एक करके सारी चालें उलटी पड़ी हैं। उनका दुर्भेद मुख्य शत्रु युद्ध के मैदान में है। अब बहुतों के सिर कलम होंगे दिल्ली में और दिल्ली से बाहर, जबकि बोफोर्स घोटाला और उभरेगा। आगामी दिनों में बहुत पटाखेबाजी होगी, जो कि नोबेल का मुख्य धंधा था—डायनामाइट के ईजाद के पहले।

विपक्ष भी चुस्त रहेगा और उसे चुस्त रहना भी चाहिए। विपक्ष की स्थिति आशा से बेहतर रही है। खासकर संसदीय उपचुनावों में। यह स्थिति और बेहतर हो सकती थी और विपक्ष मेघालय के तुरा को छोड़कर तमाम संसदीय सीटें जीत सकता था। हिंदी भाषी क्षेत्र में शासक दल की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है।

किंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान में विपक्षी दल—मुख्यत: लोकदल-ब और जनता पार्टी-चुनाव के आखिरी क्षणों तक आपस में ही गुत्थमगुत्था होकर मतदाताओं को परस्पर विरोधी संकेत देते रहे। तिस पर भी जहां कांग्रेस को कामयाबी मिली, वह बहुत अधिक वोटों से नहीं। यहां तक कि अर्जुन सिंह भी १० हजार से कम वोटों से जीते। इस बार विधानसभा उपचुनावों में उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र कोई लहर भी नहीं रही जैसा कि १९७७ और १९८५ में थी। यह विपक्ष की असफलता थी। वह मौके का लाभ उठाने में नाकाम रहा। यह संभव है कि विपक्ष अगली बार सफल हो बशर्ते विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्ष के सर्वोच्च नेता होकर उभरें और विपक्ष को नेतृत्व देने में सफल हों। उनके नेतृत्व की परीक्षा भी अभी राष्ट्रीय स्तर पर होनी बाकी है। इस बार तो वह इलाहाबाद में ही फंसे रहे और इस दौरान एक बार भी वहां से निकलकर बाहर नहीं गये।

ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में राजनीति बहुत संकुचित होती जा रही है। राजनीतिक मुद्दे अब अहम रोल अदा नहीं करते। किंतु यह बात सही नहीं। इलाहाबाद का चुनाव एक तमाशा बन गया था, जिसमें टीवी कलाकार से लेकर करतबबाज तक मंच पर आ गये थे। किंतु यही तो भारतीय शैली है। हम हरेक चीज को मेले में बदल देते हैं। वह चाहे ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रीय भवन हो या शंकरानंद की बोफोर्स जांच समिति। किंतु इस बार मतदाता ने बड़ी जिम्मेदारी और सूझबूझ का परिचय दिया है। उसने गुनहगारों को सजा दी है, भले ही वह सुनील शास्त्री के चोले में आया हो और उन लोगों को इनाम दिया है, जो उसके हकदार थे। बहरहाल मतदाताओं ने ऐलानिया कह दिया है कि शासक दल और विपक्ष दोनों की स्थिति अस्थायी है और वह यदि नहीं संभले, तो १९८९, अथवा जब भी अगले चुनाव हों, में उनकी हालत बिगड़ सकती है। यदि विपक्ष एकजुट हो सके और चंद्रशेखर जैसे बड़ी भूख वाले छोटे आदमी को उनकी औकात जता सके, तो वह दूसरे १९७७ की उम्मीद कर सकते हैं।

और यदि कांग्रेसी भी नहीं सुधरे, तो उन्हें भी १९७७ की तरह मुंह की खानी पड़ सकती है। इतिहास अपने आपको दोहराने वाला है। इस बात का अहसास शासक दल और विपक्ष दोनों को नहीं है। किंतु ऐसा ही हमेशा होता है—जब इतिहास अपना तुरुप चाल चलता है।

—जय दुबाशी

एक केंद्रीय मंत्री का व्यवहार

संतोष मोहन देव

चुनाव के कुछ दिनों पूर्व स्थानीय गोल्फ कोर्स में श्री संतोष मोहन देव की मुलाकात शहर के एक सुप्रतिष्ठित बंगाली व्यक्ति से करायी गयी, जिनका शहर में अच्छा-खासा प्रभाव है। देव ने उनसे मिलकर खुशी का इजहार किया और बातचीत से लगा कि देव पहले से ही उन्हें जानते हैं। संभवतः इलाहाबाद आने पर देव ने शहर के ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिनका उपयोग कांग्रेसी चुनाव प्रचार के लिए किया जा सके।

एक दो दिनों बाद बंगाली महाशय की मुलाकात देव से कहीं और हुई, तो उन्होंने देव को अपने निवास स्थान पर भोजन पर आमंत्रित किया। 'हां' या 'न' कहने के बजाय देव उत्तेजित हो उठे और बड़े आवेश से बोले, "छोड़िए, मुझे मालूम है कि स्थानीय कालीबाड़ी में प्रसाव के साथ लोगों को वीपी सिंह के समर्थन में पर्चियां बांटी जा रही हैं। यह बहुत गलत बात है।" बंगाली महाशय देव का आवेश देखकर स्तब्ध रह गये। उन्होंने अपने को संभाला और शांत भाव से बोले, "कालीबाड़ी में क्या होता है, क्या नहीं, उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूं? कालीबाड़ी मेरे नियंत्रण में तो है नहीं। फिर भी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, वह कतई सच नहीं हो सकता।"

बजाय संतुष्ट होने के देव और भी अधिक बौखला गये और उन्होंने बंगाली महोदय के साथ काफी अशिष्ट व्यवहार किया। बंगाली महोदय तब से काफी क्षुब्ध हैं। कारण स्वाभाविक है। वह बड़ी लगन से कांग्रेस प्रचार में लगे हुए थे। इलाहाबाद में प्रचार के लिए आये तीन केंद्रीय मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी, अजीत पांजा व नारायण दत्त तिवारी को अपने साथ लिए वह जगह-जगह मुलाकातें व सभाएं करने में बड़ी तन्मयता से कार्यरत थे। संतोष मोहन देव की अशिष्टता से उन्हें काफी सदमा पहुंचा व निराशा मिली। साथ ही, यह बात भी सामने खुलकर आयी कि कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रक्रिया बिलकुल अव्यवस्थित थी और इलाहाबाद में पधारे राज्य व केंद्रीय मंत्रियों की कार्यशैली में तालमेल नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी, न तो मुंशी और न ही पांजा या नारायण दत्त तिवारी ने श्री संतोष मोहन देव को बताया कि संभ्रांत बंगाली सज्जन कांग्रेस चुनाव प्रचार में किस तरह उन्हें सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। नतीजा हुआ देव का बंगाली महोदय के साथ अभद्र व्यवहार।

ऐसी ही अन्य शिकायतें भी सुनने में आयीं। जनमानस से कटे कांग्रेसी नेता व मंत्रीगण कांग्रेसी उम्मीदवार सुनील शास्त्री को जिताने के लिए व्यस्त तो थे, परंतु यथार्थ से हटकर। न ही उन्हें स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं का ज्ञान था और न ही उनमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दिलों को जीतने की व्यवहार कुशलता थी। एक अजीबोगरीब कृत्रिमता थी—उनकी कार्यशैली में और निस्संदेह आज के मतदाता, विशेषतः इलाहाबाद के जागरूक लोग, जिन्होंने देश को तीन प्रधानमंत्री दिये हैं, अब अच्छी तरह परखने लग गये हैं कि कौन जननेता है और कौन अपने निजी स्वार्थों का अनन्य भक्त। अन्ततः चुनाव-परिणाम इस सत्यता का परिचायक सिद्ध हुआ। ■

बेचारे सुनील क्यों हारे ?

हार का हाहाकार तो हार से पहले ही मच गया था। यह थी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। कौन था खास तौर पर इसके लिए जिम्मेदार? कांग्रेस की टीम के सिपहसालार गुलाम नबी आजाद, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा।

क्यों हुई कांग्रेस की हार, जब उनका प्रत्याशी-था बेदाग। न थी पैसे की कमी, न मोटरों की दिक्कत, दौलत या वाहनों की कमी असलियत में कभी भी महसूस नहीं हुई। पैसे और मोटरों की इफरात से लोग हैरत में थे। एक कांग्रेसी ने खुद कहा था, "इतनी मोटरें, इतने ऐशो आराम, अरे बाप रे बाप!" एक साहब और बोल पड़े, "इस भयानक तपन में इलाहाबाद के काफी कार्यकर्ताओं को पानी से ज्यादा है पेट्रोल की प्यास।" इतना कहकर वह सब कुछ कह गये। मैं इस लेख में नम्बर वार सुनील शास्त्री की हार के कारण नहीं बताऊंगा, बल्कि सुनाता चलूंगा—वे बातें जो मैंने खुद देखीं और सुनीं। कम-से-कम कोई तालमेल जैसी चीज थी ही नहीं। ज्यादातर नेतागण और मंत्रीगण एक दूसरे की नफासत और निहायत खामोशी से टांग घसीटते थे। इन सबका पहला मकसद चुनाव जीतना नहीं, बल्कि राजीव गांधी को किसी-न-किसी तरह यह खबर पहुंचाना था कि वह जान जायें कि उन्होंने भी चुनाव में खूब काम किया। काफी विधायक मुख्यमंत्री का मुंह और मूड ताकने की फिराक में रहे, जिससे जीतने के बाद वह भी मंत्रिमंडल में ठूंस दिये जायें। कई मंत्री मुख्यमंत्री की हां-में-हां मिलाते रहे जिससे बाद में उन्हें बेहतर विभाग सौंपा जाये। बहुत से कार्यकर्ता, मंत्रियों की मोटरें केंद्रीय कांग्रेस चुनाव दफ्तर में देखते ही बदहवास भागते थे और कुछ-न-कुछ भुनाने की जुस्तजू में लग जाते थे। एक दिन एक साहब अपना मुंह लटकाये मुझसे कह रहे थे कि उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्हें वाहन भी नहीं मिला है, न कोई और सुविधा। इतने में एक मंत्री की मोटर कार्यालय में घुसी। उसे देखते ही वह महोदय मुझे धता बताकर दौड़ पड़े और जेब में से कोई कागज वगैरह निकाला। हम उनकी पिछाड़ी ताकते रह गये।

चुनाव के दौरान एक महिला पत्रकार मेरे घर आयीं। कभी काफी खिन्न मालूम होती थीं, कभी काफी खुश। मैंने कहा, "आप तो सोचती होंगी कि कांग्रेस जीत ही जायेगी।" यह सुनते ही उनके चेहरे पर गुस्से का उफान आ गया। वह बोलीं, "कल हम कुछ लोग सर्किट हाउस में नेताओं और मंत्रियों से मिलने गये। दो तीन दरवाजे धीरे-धीरे खटखटाये। मालूम हुआ मंत्रीजी वगैरह खर्राटें ले रहे हैं। हम लोगों को खिसियाहट में कुछ शरारत सूझी, फिर दस-ग्यारह दरवाजों पर हाजिरी दी। नेता और मंत्री सभी गहरी नींद में सो रहे थे।" ऐसे कांग्रेस जीतेगी। कुछ ऐसी ही बातें दूसरे साहब ने सुनायीं। उन्होंने कहा था, "एक दिन कुछ होटलों और सर्किट हाउस में हम दोपहर के समय गये थे, यह सोचकर कि मंत्री और नेता लोग खाना खाने तो आयेंगे ही। उनसे चंद मिनट बात करने पर कुछ खबर तो मिलेगी ही। वहां पता लगा कि ज्यादातर खबर देने वाले वातानुकूलित गुफाओं में निद्रा से चिपटे लम्बायमान हैं। अगर मार खाने का डर न होता, तो मैं बड़ी सुरीली और बुलंद आवाज में एक दो के दरवाजे पर यह गाता:

किस गफलत की नीद में रहे चचा तुम सोय,
चचा, सत्ता का नशा तुमको मालूम होय।

एक दिन बाहर से आये एक पत्रकार ने बड़े गम और हैरत से कहा कि वह सर्किट हाउस में एक ऐसे आदमी से मिलने गये थे, जिसे वह सुनील शास्त्री का सच्चा हितैषी समझते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील के बारे में बड़ी उम्मीदों के साथ बात करना शुरू किया। कुछ समय बाद सुनील के 'हितैषी' बोले, "अरे भाई! चुनाव-वुनाव तो चलता ही रहता है, चलो एक प्याला काफी पियें।" काफी पी गयी, बात हुई करीब दो घंटे क्रिकेट की। अगर फिराक गोरखपुरी जिंदा होते और यह किस्सा उनको सुनाया जाता, तो वह अपने तरीके से कहते, "जी हां ऽऽऽ, देखिए चुनाव ऐसे लड़ा जाता है।" यह कहते हुए उनकी बड़ी-बड़ी आंखें हिकारत का छिड़काव करती दीख पड़तीं।

'राम' भगवान स्टूडियो से भागकर चुनाव की अपवित्र धरती पर आ धमके। इलाहाबाद को सबक सिखाने की शक्ति गंगा ने प्रदान की है। राम को भी पता चल गया कि प्रयाग राज में मूर्खों का जखीरा नहीं है और यहां लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। 'राम' का प्रयाग में आना कांग्रेस के लिए एक तरह की कयामत थी। लोगों ने बताया कि जैसे ही वह बोलने खड़े हुए जनता ने खिसकना शुरू कर दिया। एक साहब ने यह गाना शुरू कर दिया:

"प्रयाग में आकर राम फंसे,
हनुमान तुम्हारा क्या होगा?
राम पे सारा देश हंसा,
लक्ष्मण अब तुम्हारा क्या होगा?"

पुराने कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी ने साफ-साफ कहने की हिम्मत की कि राम को चुनाव में बुलाना उनकी राय में भूल थी। उनके बयान से करीब-करीब सभी समझदार लोगों को राहत हुई। बहुतों ने खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस में अब भी कुछ सही बात कहने वाले हैं। अगर त्रिपाठी न आते, उन्हें आधिकारिक रूप से किसी ने बुलाया नहीं था, तो कांग्रेस की और भी बुरी तरह हार होती। वह तो इसलिए आये कि उनके कुछ नजदीकी लोगों ने उनसे आने का आग्रह किया था। वह अस्वस्थ होते हुए भी इसलिए आये, क्योंकि सुनील शास्त्री उनके पुराने मित्र और साथी लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लाल बहादुरजी की मृत्यु इस चुनाव में दूसरी बार हुई। मुझे बड़ा कष्ट है, लाल बहादुरजी का नाम इस चुनाव में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि जिसके कारण मुखालिफों को तरह-तरह के अटपटे सवाल उठाने का मौका मिला।

एक दिन खबर जोरों से उड़ी और अखबारों में भी छपा कि श्रीमान अमिताभ बच्चनजी कांग्रेस प्रचार के लिए तशरीफ ला रहे हैं। राम के आने के घातक बाण से इलाहाबाद अभी संभल भी न पाया था कि दूसरी गोली दागी जाने की आशंका उत्पन्न हो गयी। कुछ कांग्रेसियों ने कमलापति त्रिपाठी से बच्चन के बुलाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते। जो संचालक चाहें, करें! बच्चन नहीं आये, बड़ी खैरियत हुई। सुनील और भी बड़ी पराजय से बच गये, क्योंकि इलाहाबाद की जनता एक विकराल मूड में थी, जिसका नेताओं को अहसास न था।

प्रयाग में कांग्रेस के इतने मंत्री, नेता कार्यकर्ता तूफान की तरह बाहर से आये कि यहां के कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि वे अपमानित हुए और उनकी उपेक्षा की गयी। काफी कार्यकर्ता उदासीन होकर घूमने लगे। आपस की पुरानी लड़ाई कुछ समय के लिए रुक जरूर गयी, मगर काम में पूरे दिल से

और सचाई से जुटने का सवाल तक नहीं उठा। वीपी सिंह की व्यक्तिगत लहर, कांग्रेस के आपस के झगड़े और नेताओं की आरामतलबी और खुदगर्जी का शिकार कांग्रेस हुई। कांग्रेस के हिमायती अखबार 'नार्दर्न इंडिया पत्रिका' ने तो यहां तक लिखा कि कुछ कांग्रेस वाले और कुछ अफसर जनमोर्चा की खुल्लम-खुल्ला हिमायत कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और गलती की कि उसने ३-४ ऐसे नेता प्रचार के लिए भेजे जो अपने गले की ताकत, गैरजिम्मेदारी और दिमाग की कमी के लिए मशहूर हैं। इन तीन चार लोगों ने यहां आकर कांग्रेस का पैसा बरबाद किया और सुनील को नुकसान पहुंचाया। कई नेता मटकते-झटकते इलाहाबाद आये। उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं और यह अखबार में भी छप गया। वह आये भी इसलिए थे कि उनका भी नाम शहसवारों में शामिल हो जाये और राजीव गांधी जान जायें कि उन्होंने भी तीर मारा। मैंने किसी भी चुनाव में ऐसी गैरजिम्मेदारी, ऐसा हलकापन, कपट और पाखण्ड तथा झूठ-फरेब का बोलबाला नहीं देखा, जितना इस उपचुनाव में।

गुलाम नबी आजाद ने तो जनमोर्चा के नेता, उनके पैसे, उनकी मोटरों उनके तम्बू-कनातों और खाने-पीने के खर्चे का ऐसा ब्यौरा अखबार में छपवाया, जैसे वह वीपी सिंह के मुनीम हों और सारे हिसाब-किताब के खाते उन्हीं की गठरी में बंधे हों। ऐसे लाजवाब आदमी को हिंदुस्तान का आडीटर जनरल होना चाहिए था। नबी साहब को इस बात का ज्ञान ही नहीं कि जनता कांग्रेस के खर्चे और उनके बारे में चिल्ला कर क्या कह रही थी। यदि गुलाम नबी आजाद ऐसे नेताओं को शीघ्र ही नियंत्रण की रस्सी से न बांधा गया, तो वह कांग्रेस और राजीव को बच्चन के बराबर नुकसान पहुंचायेंगे।

सिद्धार्थ एक बार नौका विहार के लिए गये और केवट से बातचीत करते रहे। बातचीत करते-करते केवट ने बहुत सी समझदारी की बातें कहीं, जिससे सिद्धार्थ चकित हुए और उन्होंने उससे पूछा, "ये सब बातें आपने कहां से सीखीं?" उसने उत्तर दिया, "महाराज, दरिया से।"

मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नाव के खेवनहार, प्रयाग में पराजय के बाद, अगर कुछ बातें गंगा से ही सीख लें, तो कांग्रेस और मुल्क दोनों का भला होगा। राजीव गांधी अब भी देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। उनमें जोश, शराफत और देश प्रेम की कमी तो है ही नहीं। मगर उन्हें कुछ तौर-तरीके बदलने होंगे और कुछ लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा।

—पीडी टंडन

कुछ प्रतिक्रियायें

कांग्रेस की यहां से पराजय के सिलसिले में इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित इतिहासविद् ने गिब्बन की पुस्तक 'फाल आफ द रोमन एम्पायर' का हवाला देते हुए कहा, "यदि यह सवाल गिब्बन से पूछा गया होता, तो शायद वह यही जवाब देते कि कांग्रेस अंदर से जर्जर हो चुकी थी। इसीलिए उस पर जीत हासिल की जा सकी है।"

नगर के एक चोटी के अधिवक्ता ने कहा, "कांग्रेस पार्टी की नैतिक गिरावट उसकी पराजय की जिम्मेदार है। सादगी और सदाचार की नींव पर कांग्रेस के महान नेताओं ने जिन मूल्य-मानों की प्रतिष्ठा की थी, वे धन-वैभव की चकाचौंध में पूरी तरह नदारद हो गये। गांधी की नोआखाली और दांडी पद यात्राओं का नाम मत लीजिए। अब तो कांग्रेसी जमीन पर पैर रखना भी अपनी शान के खिलाफ समझता है।" संभव है यह वक्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। मगर इसकी पुष्टि एक मांडा निवासी की जुबानी इस प्रकार है, "ससुरवा तो आधा किलोमीटर नाहीं चला और अखबार मा दुइ किलोमीटर छपवाय दिहेस।" पास ही खड़े एक दर्शक ने तीर छोड़ा, "बिना गाड़ी सवारी के चल नहीं सकता है।" जिस पर एक किशोर ने तुक्का लगाया, "ऐसी-वैसी गाड़ी भी नहीं, एयरकंडीशंड गाड़ी।" आज कांग्रेसजन की ऐसी छवि हर आम और खास के दिमाग में नक्श हो चुकी है।

मांडा के ही नजदीकी इलाके कोरांव के एक पुराने कांग्रेसी ने कांग्रेस नेताओं के मौजूदा चुनाव-प्रचार के तौर-तरीकों पर अपना क्षोभ इस प्रकार प्रकट किया, "पैदल तो चल नहीं सकते हैं। पक्की सड़क पर बाजार-बाजार घूमत रहे। सब वोटर इन सब जगहों पर तो रहते नहीं।" इसी क्षेत्र में आनेवाले अमिलियन के एक भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के मुताबिक, "पार्टी ने सब साधन तो दिये। वर्करों को गाड़ी, खाना, पैसा, मेहनताना। मगर किसी ने भी लगन से काम नहीं किया।

गुलाम नबी आजाद ने राजा पर अतिशय धन खर्च करने का आरोप लगाते हुए १७ जून को दूरदर्शन प्रसारण में कहा था कि राजा के पास कोई अपना कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उन्होंने किराये पर लिये थे। लेकिन यह बात सही नहीं लगती। पूरनपुर (पीलीभीत) से आये गोपालकृष्ण एडवोकेट इलाहाबाद के बैरहना क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर चिलचिलाती धूप में मतदाताओं का मार्ग दर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया, "मुझे आठ दिन हुए यहां आये। मैं अपने खर्चे पर आया हूं और रात-दिन काम कर रहा हूं। मैं ही नहीं, राजा के सभी कार्यकर्ता चना-चबेना खाकर बिना गाड़ी-घोड़े के जुटे हैं।" दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता अकसर गाड़ी न मिलने, पेट्रोल उपलब्ध न होने की शिकायत भी लगाते पाये गये।

कांग्रेस पार्टी के आम आदमी से लगातार हो रहे अलगाव के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "गरीबों के बजाय अमीरों का समर्थन करने की वजह से जनमानस का विश्वास कांग्रेस से खतम हो चुका है। वह भुखमरी, गरीबी तथा शोषण से जनता की रक्षा कर पाने में असमर्थ रही है।" इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने इसी बात को विस्तार देते हुए कहा, "रुपए का अवमूल्यन कालेधन का विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीनिवेश मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार हैं।" इस सिलसिले में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लगातार हो रहे घाटे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति परिषद का लगभग १६०० करोड़ रुपए का घाटा किसी समुचित कारण के बिना ही मनमाने ढंग से बट्टे-खाते में डाल दिया गया। खास वजह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये पूंजीनिवेश का असली फायदा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और अधिकारियों की जेब में पहुंच जाता है।"

क्या वीपी सिंह मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति में कोई असरदार बदलाव ला सकेंगे? जवाब में नगर के एक जाने-माने डाक्टर की टिप्पणी है, "वीपी सिंह तो उसी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अपंग व्यवस्था के अंग रहे हैं। वह जनहितों की हिमायत करके तथा खुद को ईमानदार आदमी के रूप में पेश करके जनता को आसानी से भरमा सकते हैं। भारतीय जनमानस बेहद भोला-भाला है तथा वह अपने राजनीतिक ढांचे में किसी भी ईमानदार आदमी को सिर माथे लगाने के लिए बेचैन है। राजीव गांधी भारतीय मीडिया और जनता में इसी तरह दो साल से ज्यादा हावी रहे। देश की आर्थिक नीतियों और जनतंत्र के प्रति जनता के विश्वास की कीमत पर इस खेल का अंतहीन सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देश की राजनीतिक व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा दरअसल यह बेहद अहम सवाल है।"

फिलहाल इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधिसंख्य नागरिकों को वीपी सिंह से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें अपने चयन पर गर्व और खुशी है। बारा के एक गांव के एक किसान का कहना था, "इंका कहती है कि जनता सरकार ने आम आदमी को क्या दिया? वह तो अवसरवादी पार्टियों का गठजोड़ था। जो जल्दी टूट कर बिखर गया। मगर क्या आज कांग्रेस में कोई एका है? कांग्रेसी कहते थे कि १९७७ में जनता पार्टी को वोट देकर हम लोगों ने गलती की थी। मगर अब तो लगता है कि हमने कांग्रेस को कुरसी पर बिठाकर गलत किया। वे भी तो वही गलतियां कर रहे हैं।" जनता में कुछ इसी तरह की सोच उभर रही है। मतदाता कुछ भी कर सकता है। वीपी सिंह की जीत ने इसे बेशक साबित कर दिखाया है।

इलाहाबाद उपचुनाव/**'माया' जनमत सर्वेक्षण**

यदि अमिताभ बच्चन खड़े होते तो...

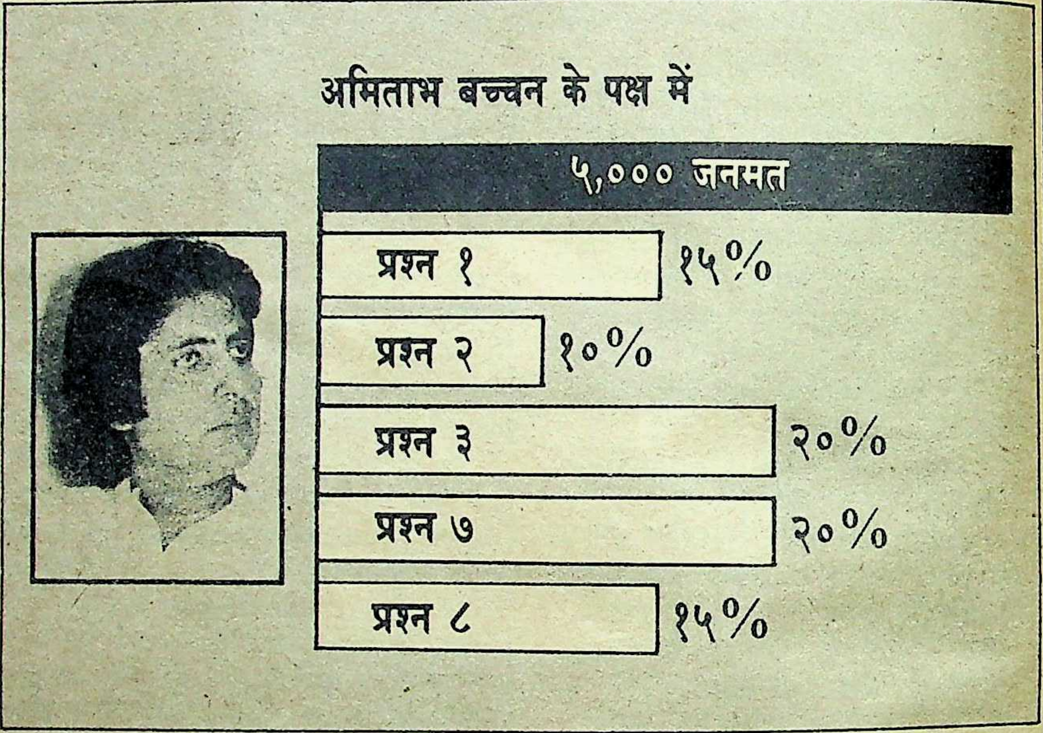

चुनाव-दौरा करके लौटे एक केंद्रीय मंत्री ने सर्किट हाउस के अपने ठंडे कमरे में धम्म से कुरसी पर बैठते हुए निराश स्वर में कहा, "अमिताभ बेटर कैंडिडेट होता।" आस-पास बैठे अन्य इंका नेताओं ने इस पर अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया और माहौल बहसनुमा बन गया। लगा चुनाव माहौल पूरे जोम पर है, लेकिन अमिताभ बच्चन का भूत अब भी मंडरा रहा है। 'माया' ने सोचा, क्यों नहीं इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करवा लिया जाये। लेकिन लगे हाथ हमें उस आंधी को भी भांपना था जो ऐसे निर्णायक चुनावों के तीन-चार दिन पहले चलती है। इलाहाबाद में खजाना खोले बैठे कांग्रेस के खजांची सीताराम केसरी ने भी पत्रकारों से कहा था, "आप जानते हैं कि उत्तरी भारत में आखिरी क्षणों में चुनाव-दृश्य बदलता है।" पिछले तीन चुनाव इसके उदाहरण हैं। १९७७ में तीन-चार दिन पहले ही यह आभास हो गया था कि जनता लहर है। इसी तरह १९८० में इंदिरा लहर और १९८४ में सहानुभूति लहर चली थी। इसलिए अमिताभ की लोकप्रियता को मापने, लहर की दिशा को चीन्हने और चुनाव के मुख्य मुद्दों को समझने के लिए 'माया' ने ११ से १३ जून की अवधि में यह जनमत संग्रह किया, जिसमें कुल ९ सवालों पर मतदाताओं की राय जानी। इस संग्रह के तहत हमने ५००० मतदाताओं को नमूना बनाया। हमने केवल साक्षर मतदाताओं को ही नमूना बनाया था। इन मतदाताओं में .४ प्रतिशत को छोड़कर सभी ने बेझिझक अपनी राय जाहिर की और सर्वे फार्म पर अपने हस्ताक्षर भी किये।

यह उल्लेखनीय है कि 'माया' ने जनवरी-फरवरी में भी एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था जो २९ फरवरी के अंक में प्रकाशित हुआ था। उस सर्वे में अमिताभ बच्चन, विश्वनाथ प्रताप पर हावी थे। लेकिन हाल के सर्वे में स्थिति बिलकुल उलट दिखायी पड़ी। मतदाताओं से बातचीत के बाद इसके मुख्य रूप से दो कारण उभर कर आये। पहला, उस समय मतदाताओं को यह भ्रम था कि जो सड़कें आदि बन रही हैं, उनके पीछे अमिताभ बच्चन हैं। लेकिन चुनाव-प्रचार के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थकों ने स्पष्ट किया कि ये सड़कें आदि कुंभ मेले की तैयारी का हिस्सा हैं, जिन्हें कांग्रेस-इ चुनाव में भुना रही है, वैसे ही जैसे मतदान के सात-आठ दिन पहले हैंड पंप लगा कर मतदाताओं को फुसलाने का असफल प्रयास किया गया।

मतदाताओं की राय बदलने का दूसरा कारण है अंतिम समय तक यह प्रचार करना कि अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन अंत में उनका मैदान से भाग जाना। इससे मतदाताओं के मन में धारणा बनी कि राजा जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें दम है और इसीलिए अमिताभ बच्चन ने राजा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा राजा को झूठा साबित करने की रणनीति का भी मतदाता पर उलटा असर पड़ा है। कांग्रेस-इ की ओर से निरंतर यह मुनादी होती रही थी कि अमिताभ बच्चन को ही खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अंत में सुनील शास्त्री को पिछले दरवाजे से कचहरी में लाकर नामांकन करवा दिया। इससे मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस-इ सार्वजनिक रूप से झूठ बोलती है और जनता को मूर्ख बनाती है। रही-सही कसर कांग्रेस-इ के परस्पर विरोधी बयानों ने पूरी कर दी। स्मरणीय है कि कांग्रेस-इ के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने २३ मई को इलाहाबाद में पत्रकारों से कहा था कि अमिताभ बच्चन बीमार हैं और उनका इलाज 'यूरोप' में हो रहा है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सके। यहां तक कि 'दूरदर्शन' ने भी यह खबर प्रसारित की। फिर राजीव गांधी ने रांची में कहा कि अमिताभ व्यस्त होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सके। इस बीच पीटीआई न्यूज एजेंसी की खबर छपी कि अमिताभ बच्चन बंबई में शूटिंग कर रहे हैं।

अमिताभ के खड़े होने की खबर 'माया' के दिल्ली और इलाहाबाद कार्यालय में भी कांग्रेस-इ आलाकमान के करीबी लोगों ने 'प्लांट' की थी। लेकिन चुनाव-प्रचार के लिए इलाहाबाद आये कांग्रेस-इ के एक उच्च-पदस्थ सूत्र ने 'माया' को जानकारी दी कि अमिताभ के नामांकन भरने के लिए इलाहाबाद पहुंचने की खबर 'प्लांट' नहीं की गयी थी, बल्कि सच्ची थी। उक्त सूत्र का कहना है कि २१ मई को कांग्रेस-इ आलाकमान ने यह तय कर लिया था कि अमिताभ को नहीं खड़ा किया जायेगा, लेकिन २२ मई को कुछ ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस-इ को लगा कि अमिताभ के बिना कोई चारा नहीं है। उस समय तय हुआ कि अमिताभ जहां कहीं भी हों, उनको विशेष विमान से इलाहाबाद पहुंचाया जाये। लेकिन अमिताभ का कहीं पता नहीं था। दरअसल, २२-२३ मई को अमिताभ बंबई में थे, लेकिन अपने घर 'प्रतीक्षा' में नहीं, सहर हवाई अड्डे

के पास नवनिर्मित एक आलीशान होटल 'लीला पेंटा' के एक कमरे में फोन आदि काट कर छिपे बैठे थे। नतीजतन उनको खोजा नहीं जा सका।

आखिरी समय तक प्रत्याशी को लेकर इस ऊहापोह की स्थिति ने कांग्रेस-इ को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल, कांग्रेस-इ तात्कालिक नीति के तहत प्रत्याशियों का चयन करती है। १९८४ में अमिताभ बच्चन को तात्कालिक आवश्यकता के तहत ही हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने के लिए खड़ा किया गया था। एक वरिष्ठ कांग्रेसी के अनुसार, "कांग्रेस-इ को अपने उम्मीदवार बनाते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र में काम करने की स्थिति में है या नहीं। क्या अमिताभ बच्चन के बारे में आलाकमान को नहीं पता था कि वह इलाहाबाद में रहकर काम नहीं कर सकते हैं?" एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, "जब अमिताभ बच्चन 'फैंस क्लब' जैसा समानांतर संगठन खड़ा करके कांग्रेस के बजाय अपनी छवि बनाने में लगे थे, तो आलाकमान ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इससे कांग्रेस की छवि तो खराब हुई ही, पारंपरिक कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रुष्ट हुए। अमिताभ ने चुनाव के समय आसमानी वायदे किये थे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। यह जानते हुए भी आलाकमान अंतिम समय तक उनको खड़ा करने के लिए हाथ पैर मारता रहा। यदि सुनील शास्त्री के नाम की घोषणा पहले कर दी होती, तो आज स्थिति यह नहीं होती।"

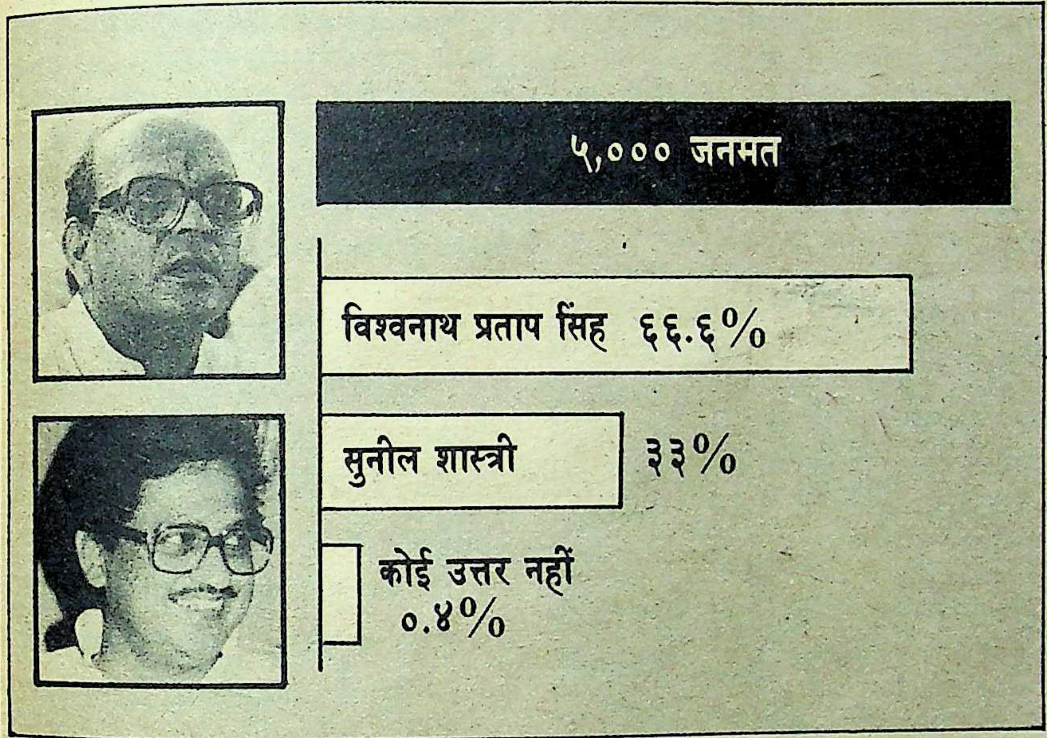

बहरहाल, इस जनमत संग्रह के दौरान यह जाहिर हुआ कि अमिताभ संबंधी इस सारे घटनाचक्र का मतदाता पर बुरा असर पड़ा है। यहां प्रस्तुत है, सवालों के अनुसार सर्वेक्षण परिणाम:

सवाल-१ : क्या अमिताभ बच्चन के कारण इलाहाबाद की कोई तरक्की हुई है?

सर्वेक्षण के तहत आये अधिकांश (८५ प्रतिशत) मतदाताओं की मान्यता है कि इलाहाबाद की तरक्की के लिए अमिताभ के वायदों पर भरोसा करके जो उम्मीदें लगायी गयी थीं, वे पूरी नहीं हुई हैं। एक देहाती का कहना था, अमिताभ यहूं फिल्मी कलाकारी दिखाय गये। वायदे तो बहुत किहिन, लेकिन मुहौं नाय दिखायन और राजनीति छोड़ दिहिन।"

सवाल-२ : कांग्रेस पार्टी को अमिताभ बच्चन से क्या कोई फायदा हुआ है?

९० प्रतिशत मतदाता, यहां तक कि सुनील शास्त्री के चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेसी भी यही मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अमिताभ से फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। यदि अमिताभ इस्तीफा देने के पहले इलाहाबाद में एक आमसभा करके सारी बातों का खुलासा कर देते, तो उनके साथ-साथ कांग्रेस-इ पार्टी की भी साख जम जाती। एक मतदाता का कहना था, "उनसे कांग्रेस-इ को सिर्फ एक फायदा हुआ कि तेज-तर्रार विपक्षी नेता बहुगुणा संसद में नहीं पहुंच सके।" लेकिन इस उपचुनाव ने जिन मुद्दों को उठाकर चुनाव जीता है, वे अमिताभ के कारण ही उठे हैं।

सवाल-३ : यदि अमिताभ चुनाव लड़ते, तो क्या स्थिति होती?

'माया' सर्वेक्षण में ८० प्रतिशत मतदाताओं की राय थी कि अमिताभ हार जाते और छीछालेदर का शिकार होते, राजीव गांधी। एक मतदाता का कहना था, "अमिताभ खड़े होते, तो राजा का हमला और भी तेज होता और उनको सुनील शास्त्री जितने भी वोट नहीं मिलते।"

सवाल-४ : नामांकन के आखिर तक कांग्रेस-प्रत्याशी का नाम गुप्त रखकर कांग्रेस-इ को कुछ फायदा हुआ?

९० प्रतिशत मतदाताओं की राय है कि कांग्रेस-इ को कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि उस दिन तो कांग्रेस-इ के तंबू ही उखड़ गये थे और इलाहाबादवासियों को यह महसूस हुआ था कि कांग्रेस-इ के नेता उन्हें मूर्ख समझते हैं। लेकिन एक मतदाता का यह भी कहना था, यदि कांग्रेसी नेता अमिताभ के न आने की पहले घोषणा कर देते, तो कांग्रेस-इ जिंदाबाद का नारा लगानेवाला भी वहां ढूंढ़ने से नहीं मिलता।"

सवाल-५ : अमिताभ के चुनाव न लड़ने पर क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए था?

६६.६ प्रतिशत मतदाताओं की राय में सिंह का चुनाव लड़ना उचित है। एक मतदाता का तर्क था, "कांग्रेस-इ अपने प्रत्याशी की घोषणा में सरासर चालाकी बरत रही थी, यदि नामांकन के दिन ही सबेरे कांग्रस-इ अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देती, तो राजा साहब पर अपने वचनों से मुकरने का आरोप लग सकता था। फिर कांग्रेस-इ के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने चुटकी ली थी कि सुनील शास्त्री जैसे मजबूत प्रत्याशी से डर कर राजा मैदान से भाग रहे हैं। इसे राजा ने चुनौती के रूप में लिया।"

सवाल-६ : क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह झूठे हैं?

सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश (६६.६) प्रतिशत मतदाता वीपी सिंह को झूठा नहीं मानते।

सवाल-७ : कांग्रेस-इ का बेहतर प्रत्याशी कौन होता—सुनील शास्त्री या अमिताभ बच्चन?

८० प्रतिशत मतदाताओं ने सुनील शास्त्री को बेहतर प्रत्याशी माना है। एक वृद्ध कांग्रेसी ने कहा, "अमिताभ का तो शहर में घुसना मुश्किल हो जाता। 'फैंस क्लब' के कुछ लोगों को छोड़कर कोई उनका साथ नहीं देता।"

सवाल-८ : यदि चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं, तो क्या कांग्रेस-इ को लाभ होता?

८५ प्रतिशत मतदाता ऐसा नहीं मानते। एक मतदाता की टिप्पणी थी, "अमिताभ के आने से कांग्रेस-इ का सारा चुनाव प्रचार ही अस्त-व्यस्त हो जाता और उन्हें नापसंद करने वाले उनकी खिलाफत करते। फिर इस मौसम में अमिताभ दो कदम नहीं चल सकते थे।"

सवाल-९ : सुनील शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह में आप किसको चाहेंगे?

६६.६ प्रतिशत मतदाताओं ने खुलकर कहा कि वे विश्वनाथ प्रताप सिंह को चाहते हैं और उन्हें ही अपना वोट देंगे। ३३ प्रतिशत ने सुनील शास्त्री को पसंद किया और .४ प्रतिशत मतदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया।

इस सर्वे के दौरान बातचीत से यह बात सामने आयी कि कांशी राम कांग्रेस-इ को ज्यादा और विश्वनाथ प्रताप सिंह को कम क्षति पहुंचायेंगे।

लोकसभा उपचुनाव

सत्ता पर मतदाता की नाराजगी भारी

लोकसभा की ७ और विधानसभाओं की ११ सीटों के लिए १६ जून को हुए उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस-इ और उसकी सरकार के खिलाफ देशवासियों के आक्रोश को खुलकर जाहिर कर दिया है। देश की राजनीतिक सत्ता में निर्णायक भूमिका वाले उत्तर प्रदेश में तो इस जनाक्रोश ने इंका विरोधी लहर का रूप लेकर सत्तारूढ़ दल का सफाया ही कर डाला। इसमें शक नहीं कि यदि देश के अन्य भागों में भी ऐसा ही एकजुट विपक्ष मिल जाता, तो कांग्रेस-इ की नैया डूबी ही थी। गुजरात और राजस्थान में जो कुछ उसे सफलता मिली, वह बहुत कुछ विपक्षी घटकों के आपसी टकराव और बिखराव के कारण ही मिली। सात राज्यों में हुए इस उपचुनाव में हरियाणा की फरीदाबाद संसदीय तथा ताबड़ू विधानसभा सीट की मतगणना कांग्रेस-इ की शिकायत पर जांच-पड़ताल के लिए चुनाव आयोग ने रोक दी है। उपचुनाव के घोषित ६ संसदीय परिणामों में से मात्र दो इंका के पक्ष में गये हैं। इसी प्रकार १० विधानसभा सीटों में से सत्तारूढ़ दल को जैसे-तैसे ५ सीटें पाकर ही संतोष करना पड़ा।

लोकसभा उपचुनाव: संसदीय उपचुनावों का पहला नतीजा राजस्थान के पाली क्षेत्र से मिला था, जिसके साथ सत्तारूढ़ दल ने अपना खाता खोला। लेकिन जिस सीट पर दुनिया भर की नजर कांग्रेस पार्टी तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सारी ताकत लगी थी, उसे बुलंद मार्जिन के साथ हासिल कर संयुक्त विपक्ष के जनमोर्चा प्रत्याशी वीपी सिंह ने इलाहाबाद को पहले स्थान पर अंत तक बनाये रखा। इस नतीजे ने न केवल सत्तारूढ़ दल के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिये, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य में इंका को उसकी बेहाली का अहसास भी करा दिया। (देखें आवरण कथा)

पाली: राजस्थान की पाली संसदीय सीट विपक्ष में आपसी टकराव की बदौलत कांग्रेस-इ बचा ले गयी। जीत-हार में महज ३९ हजार वोटों का फासला यह बताता है कि हवा खराब थी। लोकदल और भाजपा में अगर तालमेल बैठ गया होता, तो यह सीट हाथ से जाने ही वाली थी।

यह सीट कांग्रेस-इ सांसद मूलचंद डांगा के निधन से खाली हुई थी। १९८४ में डांगा ने भाजपा की कु० पुष्पा जैन को थोड़ी-सी मार्जिन से हराया था। किंतु १९८५ के विधानसभा चुनाव में पाली संसदीय क्षेत्र की ८ विधानसभा सीटों में से भाजपा ने ३ सीटें जीत ली थीं। इसी आधार पर पार्टी ने इस संसदीय सीट पर दावा किया और अन्य विरोधी दलों से भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने को कहा। इसके प्रत्याशी सामाजिक न्याय क्षेत्र में मशहूर और गोहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा थे। लेकिन राजस्थान के जपा प्रमुख कल्याण सिंह कालवी और लोकदल नेता नाथूराम मिर्धा ने भाजपा का दावा न मानकर संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में सुखलाल सेणचा को लोकदल के टिकट पर लड़ा दिया। इस विपक्षी विवाद से कांग्रेस-इ का रास्ता आसान हो गया। प्रारंभ में सत्तारूढ़ पार्टी भी आपसी विवाद में फंस गयी थी। इंका टिकट के कई अन्य दावेदार थे, जो टिकट न मिलने से क्षुब्ध और अधिकृत प्रत्याशी शंकर लाल के खिलाफ हो गये थे। लेकिन भाजपा और लोकदल की आपसी खींचतान में विपक्ष को यह सुनहरा मौका भी रास नहीं आया। पाली जिले में चुनाव पर खासा असर डालने वाली सिखी जाति के लोग माथुर सरकार में मंत्री माधोसिंह दीवान को अपना आका मानते हैं। यह जाति इंका के समर्थन में थी। लोकदल उम्मीदवार चेणसा इसी जाति के होने के कारण इंका का यह गढ़ तोड़ सकते थें, लेकिन भाजपा से भिड़ंत के कारण जातिवालों ने इनका भविष्य पहले ही पढ़ लिया। विपक्ष के नेता भैरों सिंह शेखावत ने इस उपचुनाव को निर्णायक मानकर लोढा को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन जपा-लोकदल एका की दिलचस्पी इंका प्रत्याशी को हराने के बजाय शेखावत की रणनीति ध्वस्त करने में ज्यादा थी। सेणचा के चुनाव-प्रचार के लिए आये हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने भी यही किया। विपक्ष के दोनों गुट एक दूसरे की बखिया उधेड़ते रहे। इंका के खिलाफ कहने के लिए इनके पास दो ही बातें थीं: एक, सूखा राहत में भ्रष्टाचार की और दूसरी एक मंत्री से जुड़े कथित रंगरेली कांड की। दूसरी ओर प्रदेश इंका प्रमुख अशोक गहलौत और मुख्यमंत्री माथुर ने यह सीट निकालने के लिए क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और मतदाताओं के मसलों को फौरन हल किया। जहां कहीं, जिस किसी ने हैंड पंप की मांग की, तत्काल मांग पूरी की गयी। इसके अलावा राम निवास मिर्धा, भजन लाल, राजेश पायलट, बूटा सिंह आदि बड़े नेताओं के दौरे और भाषण का भी मतदाताओं पर असर हुआ।

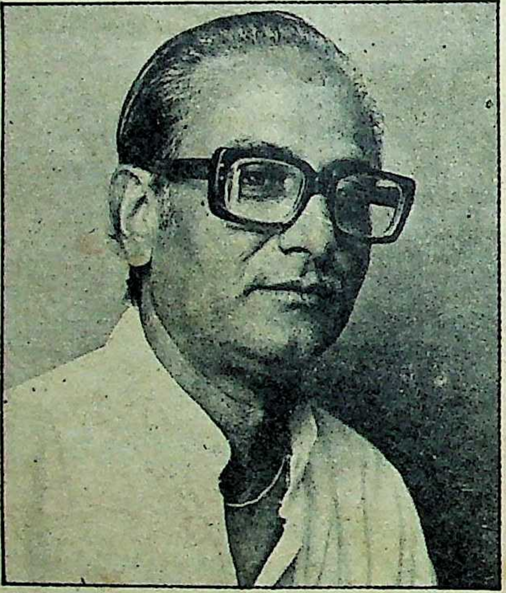

शंकर लाल

सिरसा: जिस प्रकार इलाहाबाद में मतदाताओं की संवेदना को स्व० लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर छोड कर सहानुभूति में वोट पाने का तरीका अपना कर भी सुनील शास्त्री को कोई लाभ नहीं मिला, उसी प्रकार हरियाणा के सिरसा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस-इ की उम्मीदवार कुमारी शैलजा के आंसू भी बेकार गये। लोकदल प्रत्याशी हेतराम ने उन्हें १,८५,३४४ मतों से पछाड़ कर बुलंद जीत दर्ज की। यह सीट इंका सांसद और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह के निधन से खाली हुई थी।

> इंका टिकट के कई अन्य दावेदार थे, जो टिकट न मिलने से क्षुब्ध और अधिकृत प्रत्याशी शंकरलाल के खिलाफ हो गये थे। लेकिन भाजपा और लोकदल की आपसी खींचतान में विपक्ष को यह सुनहरा मौका भी रास नहीं आया। प्रदेश इंका प्रमुख अशोक गहलौत और मुख्यमंत्री माथुर ने यह सीट निकालने के लिए क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और मतदाताओं के मसलों को फौरन हल किया।

हरियाणा में देवीलाल (लोकदल) की सरकार है, जिससे सिरसा के लोगों को फिलहाल कोई खास शिकायत नहीं थी। कांग्रेस-इ के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई दमदार मुद्दा नहीं था। चुनाव-प्रचार में भी इंका लोकदल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए इस क्षेत्र में पोस्टर-युद्ध की जगह व्यक्तिगत संपर्कों से अधिक काम लिया गया। शैलजाजी चुनाव प्रचार के इसी क्रम में एक-एक गांव में जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करती रहीं। सहानुभूति में वोट पाने की गरज से वह हर कहीं अपने स्वर्गीय पिता दलवीर सिंह की चर्चा

छेड़ने से नहीं चूकती थीं। उनका प्रचार करने भजनलाल, आस्कर फर्नांडीस, जगन्नाथ पहाड़िया आदि नेताओं के अलावा वैजयंती माला जैसी अभिनेत्री भी आयीं। लेकिन प्रचार को न आवेग मिला और न ग्लैमर, जवाब में लोकदल ने नंदमूरि तारक रामाराव (एनटीआर) को पेश कर दिया देवीलाल की दुनिया में इतना बहुत था। सत्तारूढ़ लोकदल तो प्रचार में बुलंद हौसले के साथ लगा ही था। लोकदल के चुनाव प्रचार की कमान देवीलाल के पुत्र रंजीत सिंह के हाथ में थी।

गोधरा: पूर्व गुजरात के गोधरा संसदीय उपचुनाव में इंका का विकट व्यूह भेद कर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शांतिभाई पटेल ने जीत हासिल की। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार उदयसिंह बारिया की पराजय से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का जातिवादी नुस्खा बेमानी हो चुका है। सीधा मुकाबला वाला यह उपचुनाव सत्तारूढ़ और विपक्ष की प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया था। इसलिए इस कांटे की लड़ाई में २६,८२५ मतों से मिली जीत को बुलंद ही कहा जायेगा।

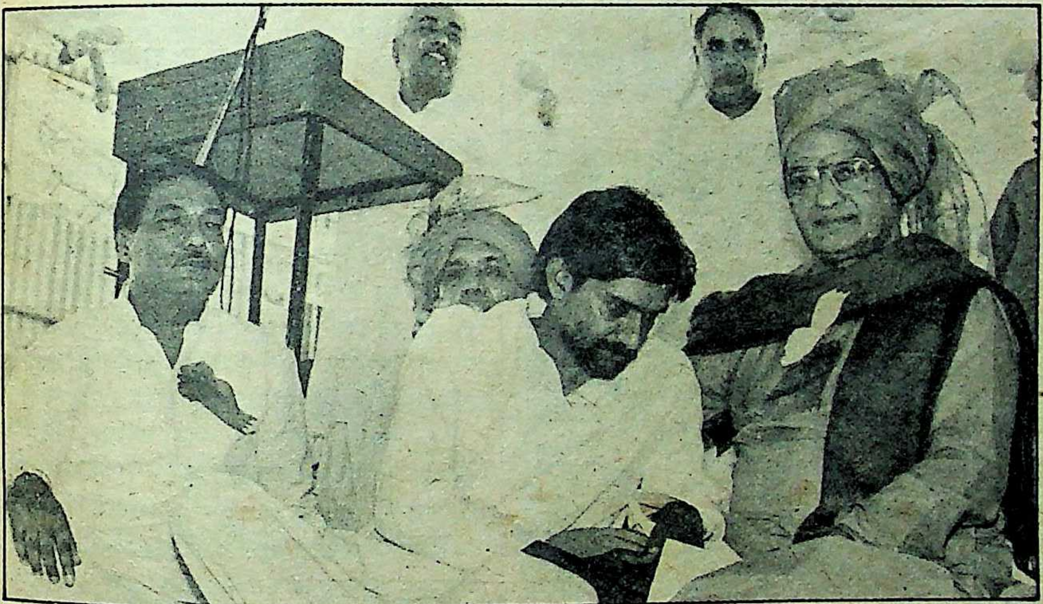

बुलंद जीत : एक जनसभा में हेतराम के समर्थन में एनटीआर

गोधरा संसदीय उपचुनाव क्षेत्र के मतदाताओं में बहुत उत्साह नहीं था। काफी हद तक पिछड़े पड़े इस क्षेत्र को एक ही चिंता खाये जा रही थी। वह थी वर्षा की चिंता, क्योंकि लगातार चौथे साल पूरे क्षेत्र पर सूखे का साया फैला हुआ था। फौरी घूस के तौर पर कांग्रेस-इ सरकार ने राहत कार्य में तेजी दिखायी, लेकिन मतदाताओं ने इस चाल को तरजीह नहीं दी।

यह उपचुनाव क्षत्रियों और पटेलों के बीच लड़ा गया। मतदाता पर गहरा असर डालने के निश्चय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी बराबर क्षेत्र में ही जमे रहे। लेकिन उनका दबदबा भी विपक्ष की ओर रुख कर आगे बढ़ी जनता पर बेअसर हो गया। इस क्षेत्र में जपा के चुनाव प्रचार का संचालन चिमन भाई पटेल ने किया। शांति भाई स्वयं रोजाना १० सभाओं को संबोधित करते थे। कोई चार सौ कार्यकर्ता दिन रात लगे थे।

यह सीट पंचमहल राजघराने से उभरे और जिले के बारिया एवं क्षत्रिय समुदायों पर जबरदस्त असर वाले जगदीप बारिया के चल बसने से खाली हुई थी। इस उपचुनाव में भी जातिवाद को लाभकारी माध्यम मानकर कांग्रेस-इ ने उदय सिंह बारिया को इस आशा से अपना उम्मीदवार बनाया कि बारिया क्षत्रिय समुदायों के ६० प्रतिशत वोट उसे मिल जांयेंगे। पार्टी के नेताओं—कार्यकर्ताओं में एक मलाल भी था कि लाख कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने इस खास उम्मीदवार के लिए गोधरा आने से इनकार कर दिया। फिर भी मोतीलाल वोरा, मोहसिना किदवई, भजनलाल आदि पार्टी के कुछेक बड़े नेता 'अभिनेता राम' (अरुण गोविल) के साथ क्षेत्र में लाये और घुमाये गये।

विपक्ष के प्रत्याशी शांति भाई पटेल पके हुए नेता होने के साथ ही क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय रहे हैं। जपा, भाजपा और जनमोर्चा ने शुरू में ही गुजरात में उपचुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला कर सीटों का तालमेल बिठा लिया था। गोधरा संसदीय सीट जपा के लिए छोड़ी गयी थी। पटेल उसके मुख्य सचेतक हैं। चुनाव-प्रचार का संचालन चिमन भाई पटेल कर रहे थे।

तुरा: मेघालय के तुरा संसदीय क्षेत्र का परिणाम कांग्रेस-इ के पक्ष में जाने वाला दूसरा और आखिरी नतीजा था। यहां भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इंका प्रत्याशी कैप्टेन विलियम संगमा ने त्रिकोणीय संघर्ष में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय लैंबर्ट संगमा को ७७५६७ मतों से हरा दिया। संघर्ष के तीसरे कोने पर हिल पीपुल्स यूनियन के ग्रहण सिंह तीसरे स्थान पर ही रहे। फसल कटाई का मौसम होने से यहां मतदाताओं में उत्साह नहीं था। पर दिल्ली और पूर्वोत्तर क्षेत्र से आये इंका नेताओं के हुजूम ने बेजान चुनाव-प्रचार में जान डाल दी। इस हुजूम में एबीए गनी खां चौधरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंका के संकटमोचक राजेश पायलट भी थे। एचपीयू उम्मीदवार को संसद में भेजने के लिए आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू जैसे नेताओं ने भी क्षेत्र का दौरा किया। कै० संगमा ने जजबाती अपील के साथ ४० वर्षों तक राज्य की अपनी सेवा के इनाम के तौर पर लोगों से वोट मांगा और घर-घर जाकर आदिवासी समुदाय के धर्मगुरु, महरियों से संपर्क किया था जिनकी सलाह ग्रामीण मतदाता कभी टालते नहीं। ३ लाख मतदाताओं वाली तुरा संसदीय सीट पर परंपरा से कांग्रेस-इ का कब्जा रहा है। १९७७ की जनता लहर में भी पार्टी के उम्मीदवार पीए संगमा ने यह सीट जीत ली थी। १९८० और ८४ में भी उन्होंने यह कब्जा बनाये रखा।

—प्रांतीय ब्यूरो के साथ वशिष्ठ

जिस प्रकार इलाहाबाद में मतदाताओं की संवेदना को स्व० लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर छोड़कर सहानुभूति में वोट पाने का तरीका अपना कर भी सुनील शास्त्री को कोई लाभ नहीं मिला, उसी प्रकार हरियाणा के सिरसा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस-इ की उम्मीदवार कुमारी शैलजा के आंसू भी बेकार हो गये। लोकदल प्रत्याशी हेतराम ने उन्हें १,८५,३४४ मतों से पछाड़ कर बुलंद जीत दर्ज की। यह सीट इंका सांसद और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह के निधन से खाली हुई थी।

लोकसभा की ७ और विधानसभाओं की ११ सीटों के लिए १६ जून को हुए उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस-इ और उसकी सरकार के खिलाफ देशवासियों के आक्रोश को खुलकर जाहिर कर दिया है। देश की राजनीतिक सत्ता में निर्णायक भूमिका वाले उत्तर प्रदेश में तो इस जनाक्रोश ने इंका विरोधी लहर का रूप लेकर सत्तारूढ़ दल का सफाया ही कर डाला। इसमें शक नहीं कि यदि देश के अन्य भागों में भी ऐसा ही एकजुट विपक्ष मिल जाता तो, कांग्रेस-इ की नैया डूबी ही थी।

विधानसभा उपचुनाव

काश विपक्ष हर कहीं एकजुट होता !

तीन दशकों में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में चली कांग्रेस विरोधी लहर ने इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से ही नहीं, मेरठ जिले के छपरौली और फैजाबाद के टांडा विधानसभा क्षेत्र से भी सत्तारूढ़ दल का पत्ता साफ कर दिया है। जनता के गुस्से और वीपी आंदोलन से उपजी इस लहर में विपक्ष की गजब की एकजुटता ने सोने में सोहागे का काम किया। फलतः इस उपचुनाव में मतदाता स्वयं सड़क पर निकल आये थे। उत्तर प्रदेश में सफाये का मतलब इंका की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी बजना होता है, इसलिए छपरौली तथा टांडा विधानसभा सीटों के लिए भी कांग्रेस-इ ने कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन लहर ने कोई तरीका कारगर नहीं होने दिया।

छपरौली: चौधरी चरण सिंह के गढ़ छपरौली (मेरठ) में कांग्रेस-इ उम्मीदवार रामपाल सिंह की स्थिति जून के पहले हफ्ते तक काफी अच्छी थी। लेकिन ९ जून को छपरौली से १२ किमी दूर किशनुपुर बराल गांव में जपा कार्यकर्ता पर पुलिस की गोलीबारी और लाठी चार्ज की घटना से फिजा ही बदल गयी। यह घटना मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के आगमन पर हुई थी, जिसमें जपा कार्यकर्ता चंद्रपाल की मृत्यु हो गयी और कई घायल हो गये। संयुक्त विपक्ष के जपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह को हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल का समर्थन भी प्राप्त था। किसान नेता महेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस को वोट न देने का आह्वान भी उन्हीं के पक्ष में गया। चुनाव-प्रचार के दौरान दोनों ओर से खूब गहमागहमी रही। कांग्रेस के भीतर टिकट देने, चुनाव प्रभारी बनाने, प्रचार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने, खर्चे देने-लेने जैसी छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े विवाद खड़े हो गये और गुट बन गये थे। इन सबका असर विपक्ष के पक्ष में गया। फलतः संयुक्त विपक्ष के जपा उम्मीदवार नरेंद्रसिंह ने इंका के रामपाल सिंह को २२ हजार मतों से हरा दिया। यह सीट लोकदल-अ (जो जपा में शामिल हो गया है) के विधायक सरोज वर्मा के निधन से खाली हुई थी। उपचुनाव में ९ निर्दल प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुईं।

टांडा: छपरौली की ही तरह टांडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी शुरू में लोकदल-ब और जनता पार्टी दोनों ने उम्मीदवार खड़े कर दिये थे। इससे कांग्रेस-इ को अनायास लाभ मिलने की आशा बढ़ गयी थी। लेकिन अंतिम क्षणों में हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल की भूमिका रंग लायी। जपा ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। यह कांग्रेस के लिए पहला झटका था कि लोकदल-ब के गोपीनाथ वर्मा संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी बना दिये गये। टांडा में इंका ने विकास के बेअसर मुद्दे पर वोट लेना चाहा, जबकि विपक्ष को बाबरी मस्जिद के संवेदनशील मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों का भी समर्थन मिला। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने चुनाव-प्रचार के दौरान मतदाताओं को धमकी दे दी, "यदि कांग्रेस को वोट नहीं मिले, तो सारे विकास कार्य रोक दिये जायेंगे।" इससे जनता और बिदक गयी। इंका में एकजुटता नहीं थी। मजलिस प्रत्याशी अब्दुल मजीद अंसारी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस का 'वोट बैंक' ही खाली कर दिया। दूसरी ओर मतदाताओं का रुख पाकर विपक्षी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच गये थे। कुर्मी बहुल टांडा में गोपीनाथ वर्मा को सजातीय होने का भी लाभ मिला। यों इंका के वयोवृद्ध विद्वान नेता मुख्तार अहमद किदवई सम्मानित तथा योग्य प्रत्याशी थे, लेकिन इन्हीं कारणों से उन्हें अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। गोपीनाथ वर्मा बुलंदी के साथ जीत गये।

किसी तरह जीते: अर्जुन सिंह

खरसिया: मध्य प्रदेश की खरसिया विधानसभा सीट मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने आखिर येन-केन-प्रकारेण जीत ही ली। अपने अस्तित्व के सवाल से जुड़ी यह सीट पाने के लिए अर्जुन सिंह को जायज-नाजायज में फर्क किये बगैर सरकारी-गैरसरकारी जिन-जिन साधनों को उपयोग में लाना और जो भी हथकंडा अपनाना पड़ा, उससे वह बाज नहीं आये। फिर भी वह भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह जूदेव को सिर्फ ९ हजार मतों से हरा पाये। यह सीट इंका विधायक लक्ष्मीप्रसाद पटेल के निधन से रिक्त हुई थी।

दरअसल खरसिया उपचुनाव में भी कांग्रेस-इ विरोधी लहर चल पड़ी थी। कांग्रेस-इ के भीतर कलह और क्षोभ भरा था। पार्टी का अर्जुन सिंह विरोधी गुट भी सक्रिय था। उधर भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह जूदेव अपनी छवि के कारण ही उपचुनाव में भारी पड़ने लगे थे। इस सीट के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यानी चुनाव का हर जायज पहलू अर्जुन सिंह के खिलाफ था। इसीलिए माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अब नाजायज हथकंडों से ही अपनी हस्ती बचा सकते हैं।

कांग्रेस-इ ने वोटरों को लुभाने-फंसाने के लिए सारे हथकंडे अपनाये। स्वयं अर्जुन सिंह के चहेते, प्रदेश कांग्रेस-इ के महासचिव एवं सांसद जगतपाल सिंह ने माना था, "खरसिया में जितने काम पिछले ४० वर्षों में नहीं हुए, उतने पिछले डेढ़ महीने में ही हो गये।" तिस पर भी मतदान के पहले ही मतपत्र बाहर आ गये।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने 'वोट लीकेज' की जांच का आदेश दिया और खरसिया में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिये। लेकिन भाजपा नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस-इ के लोग चुनाव आयोग की एक नहीं सुनते और शिकायत सही होने पर भी आयोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वह सत्तारूढ़ दल के आगे असहाय है।

खेतड़ी: लोकदल और भाजपा की जिस आपसी उठापटक के चलते विपक्ष ने पाली संसदीय सीट खो दी, उसी के कारण राजस्थान में झुंझनू जिले की खेतड़ी विधानसभा सीट भी इंका विरोधी हवा के बावजूद उसके हाथ न लग पायी। उस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डा० जितेंद्र सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हजारी लाल को १३९४३ मतों से हरा दिया। इस उपचुनाव में असली मुकाबला गूजरों और राजपूतों के बीच था। इंका और भाजपा दोनों ने गूजर उम्मीदवार खड़े किये थे। लोकदल के उम्मीदवार 'राजपूत सभा' के अध्यक्ष देवी सिंह के पुत्र प्रद्युम्न सिंह थे, जो उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहे।

लश्कर: विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश की लश्कर (पूर्व) सीट अंदरूनी खींचतान से परेशान कांग्रेस-इ लाख कोशिशों के बाद भी नहीं पा सकी। उसके प्रत्याशी हरीशचंद्र गोयल भाजपा के रघुनाथ शंकर पोटनिस से बुरी तरह पिट गये। इस सीट पर १९७० से लगातार भाजपा का कब्जा है। ग्वालियर के शहरी इलाके के लिए इंका प्रत्याशी को रेलमंत्री माधवराव सिंधिया ने नामजद किया था। ग्वालियर रेलमंत्री का गढ़ माना जाता है। किंतु मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और रेलमंत्री सिंधिया के बीच छिड़े शीतयुद्ध के कारण पहले से ही यह सीट इंका की पकड़ से बाहर दिखायी देने लगी थी।

भाजपा ने प्रचार के दौरान जगह-जगह ऐसे बोर्ड लगाये, जिनमें जनता पार्टी के समय और वर्तमान में चल रही कीमतों की सूची पेश की गयी थी। मतदाताओं के लिए ये खास आकर्षण के केंद्र थे, जहां इंका शासन में हुई चौगुनी मूल्यवृद्धि का लेखाजोखा उन्हें स्पष्टतया मिल गया।

गोहद : मध्य प्रदेश में भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट पर कांग्रेस-इ का कब्जा होना काफी पहले से निश्चित दिखायी देने लगा था। भय और शराब से प्रेरित होने वाले इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के मतदाताओं का कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। दूरदराज के गांवों में साधनहीन विरोधी दलों का पहुंचना और मतदाताओं से नाता जोड़ना ऐसे ही कठिन था। ऊपर से डकैतों का आतंक, जिन्हें कांग्रेस-इ ने अपना कार्यकर्ता बना लिया था। तीसरी, और विपक्ष के लिए सबसे घातक बात थी भाजपा और लोकदल-ब का आपसी टकराव। तीन निर्दल उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिन्होंने विपक्ष के ही वोट काटे। इतने पर भी भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक सीतराम जाटव ने कांग्रेस-इ के सोपत जाटव की जीत कठिन बना दी थी। लेकिन अंततः उन्हें सोपत सिंह से हारना ही पड़ा।

मालिया : गुजरात में जूनागढ़ जिले के गिर जंगल के निकटवर्ती मालिया विधानसभा क्षेत्र की सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा से मात खा ग़यी और भाजपा के प्रत्याशी देवानंद सोलंकी ने कांग्रेस के उम्मीदवार जेठाभाई वनेरा को १९८५ मतों से पराजित कर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसे यह सीट कांग्रेस की ही थी, परंतु सोलंकी की स्थिति शुरू से ही काफी मजबूत थी। संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी होने के बावजूद वह केवल भाजपा के बूते पर लड़े थे। इस क्षेत्र में चार सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। चुनावों को ध्यान में रखकर करीब पिछले तीन हफ्तों से राहत कार्य शुरू किया गया था, परंतु इससे भी चुनावी परिणाम में कांग्रेस को लाभ नहीं मिल सका और उसे पराजय का सामना करना पड़ा।

द्वारिका : द्वारिका (गुजरात) विधानसभा सीट पर कांग्रेस की विजय कुछ वैसी ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार डा० रणमल बरोतिया ने जनता पार्टी के रवीमजी गोजिया को ७६०७ मतों से पराजित किया। यहां के चुनाव में उम्मीदवार का व्यक्तित्व और पार्टी की नीतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं। महत्वपूर्ण यह था कि यहां के माफिया सरदार का समर्थन किसको मिलता है और किसको पुरी के शंकराचार्य का। खैर, उपचुनाव के परिणाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोड़-तोड़ की राजनीति में किसने किसके कान काटे?

बाराबानी : प० बंगाल में बर्दवान जिले की बाराबानी विधानसभा सीट चुनाव-प्रचार की कमजोरी और जन समस्याओं की उपेक्षा के कारण वामपंथी मोर्चे के हाथ से निकलकर कांग्रेस-इ के हाथ में चली गयी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के विधायक अजित चक्रवर्ती के निधन से रिक्त हुई इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में युवक कांग्रेस के नेता माणिक उपाध्याय ने सीपीएम के मज़दूर नेता सुहृद रंजन डे को ५५१ मतों से हरा दिया। यहां कांग्रेस-इ और वामपंथी मोर्चे के बीच सीधा मुकाबला था। रैलियों, सभाओं और पोस्टरबाजी में राज्य तथा क्षेत्र की उपेक्षा के लिए जहां इंका ने राज्य सरकार पर कीचड़ उछाले, वहीं मोर्चा नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मोर्चा उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में जिला स्तर के नेताओं ने ही भाग लिया। किंतु इंका प्रत्याशी के लिए अजित पांजा, प्रियरंजन दासमुंशी, प्रणव मुखर्जी आदि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी प्रचार किया। निश्चय ही माणिक उपाध्याय को इसका लाभ मिला।

कुमारग्राम : उत्तर बंगाल में जलपाई गुड़ी जिले की कुमारग्राम विधानसभा सीट क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के उम्मीदवार तालिब टप्पू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस-इ के खगेंद्रनाथ ठाकुर को २२२९८ मतों से हराकर फिर हासिल कर ली। आरएसपी प० बंगाल के सत्तारूढ़ वाम मोर्चे का एक घटक है। इस बार आरएसपी ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति बहुत ही मजबूत कर ली थी। १९८७ में पार्टी ने मात्र १३ हजार मतों की बढ़त के साथ यह सीट जीती थी।

—उप्र, मप्र और राजस्थान ब्यूरो के साथ वशिष्ठ

अलकोहल-रहित, विटामिन-युक्त, जड़ी-बूटियों से बना एकमात्र टॉनिक, जो विद्यार्थियों की मस्तिष्क-शक्ति बढ़ानें में अपनी सफ़लता चिकित्सीय तौर पर प्रमाणित कर चुका है।

अब आप सचमुच अपने बच्चे को पढ़ने-लिखने में और तेज़ बना सकते हैं—सिंकारा की सहायता से।

सिंकारा के वैज्ञानिक विश्लेषण ने सिद्ध किया है कि यह मस्तिष्क की उच्चतम कार्यकुशलता के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म तत्त्व प्रदान करता है। परीक्षणों ने दर्शाया कि जिन विद्यार्थियों को सिंकारा दिया गया, उन्होंने सिंकारा से पूर्व की अपेक्षा सिंकारा के प्रयोग के बाद अधिक प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए।

और, अलकोहल-रहित होने के कारण यह बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता।

घर-भर के लिए, प्रत्येक ॠतु में उत्तम

सिंकारा से परिवार को और भी अनेक लाभ हैं। विशेषतया, इसे इन अवस्थाओं में लेने की सलाह दी जाती है: ● साधारण कमज़ोरी व दुर्बलता ● थका देने वाले व्यायाम के बाद ● रोग से स्वस्थ होने के समय ● भूख की कमी ● शिशुओं की बढ़ोत्तरी ● स्तन-पान कराने वाली माताओं के लिए ● स्नायु थकावट व रोग की अधिकता ● विद्यार्थियों का मानसिक व बौद्धिक विकास, आदि।

सिंकारा

विश्व-प्रसिद्ध फ़ैमिली टॉनिक, प्रत्येक ॠतु में उपयोगी

अनिवार्य तत्त्वों जड़ी-बूटियों तथा विटामिनों का अनोखा मिश्रण

हमदर्द

HTA 5237H

cinkara
THE WORLD FAMILY TONIC
cinkara

'कशमकश' से 'उड़ान' तक : लगातार ४८ घंटे का कड़ा परीक्षण दौर.

हर पिरामिड टी वी को गुजरना होता है लगातार ४८ घंटे चलते रहने की कड़ी अग्नि परीक्षा से.

इस तरह की अग्नि परीक्षा के कुछ अपने फ़ायदे है.

सेट में किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी हो तो वह छुप नहीं सकती और उस को तुरंत दुरुस्त किया जा सकता है. इस प्रकार यह पक्का हो जाता है कि पिरामिड का कोई भी दोषपूर्ण सेट बाज़ार में आ ही नहीं सकता.

ज़्यादातर टी वी इस तरह का परीक्षण तो करते है पर सिर्फ़ ६ घंटे तक. कुछ एक १२ घंटे तक. और कुछ २४ घंटे... लेकिन इससे अधिक नहीं.

वेव सॉल्डरिंग : भारत के १०० से भी अधिक टी वी जो नहीं करते.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए वेव सॉल्डरिंग बिल्कुल वैसी ही ज़रूरी चीज़ है जैसी कि कपड़ों के लिए सिलाई : यानी हर जोड़ पूरे एहतियात और मज़बूती के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए.

बदकिस्मती से भारत के अधिकांश टी वी में आज भी सॉल्डरिंग हाथों से की जाती है. एक ऐसा घटिया तरीक़ा जो टी वी की परिपूर्णता में सबसे बड़ी रुकावट है.

कुछ गिने-चुने ब्राण्डों में केवल पिरामिड ही ऐसा एकमात्र टी वी है कि जिसमें इस्तेमाल की जाती है वेव सॉल्डरिंग– पूरी तरह अचूक एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया जो दिलाती है सौ-फ़ीसदी बेहतरीन कामगिरी.

बिल्कुल वही फ़र्क, जो मशीन की सिलाई और हाथ से की जानेवाली कच्ची सिलाई के बीच होता है.

टी वी की सर्विस होनी चाहिए तब, जब यह काम कर रहा हो पूरी कुशलता से.

इसे हम कहते है प्रीवेंटिव मेन्टेनेन्स यानी ख़राबी की रोकथाम करने वाली देखभाल. जिसे हम हर पिरामिड टी वी के लिए बिल्कुल मुफ़्त करते है.

पहले वर्ष के दौरान, हर तीन महीने में हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा.

वह आपके एन्टीना को ठीक-ठाक करेगा, आपके सेट की सफ़ाई करेगा, और पूरी तरह इसकी जांच-पड़ताल करेगा. यदि कोई छोटी-मोटी ख़राबी होगी, तो उसी वक़्त ठीक कर देगा.

ये तो हमारी सेवाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

आपका पिरामिड टी वी घर पहुंचने के दो हफ़्ते बाद ही कंपनी का इंजीनियर आपके घर पहुंचकर देखेगा कि आपका सेट सही तरीके से लगाया गया है या नहीं? और यह बढ़िया ढंग से काम कर रहा है या नहीं?

और इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो फ़ोन कीजिए, हमारा इंजीनियर २४ घंटे या इससे भी कम वक़्त में आपकी सेवा में मौजूद होगा!

बदकिस्मती से कभी आपका सेट मरम्मत के लिए सर्विस सेन्टर ले जाना पड़े तो बदले में हम आपको दूसरा सेट देंगे. यानी आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम 'चित्रहार' देखने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी!

दरअसल गारंटी है किसकी सुरक्षा : आपकी या निर्माता की?

आज, ज़्यादातर गारंटियां देखकर आप सोचते होंगे कि आख़िर इसका मतलब क्या है?

इनमें लंबी-चौड़ी सूची तो उन नामों की होती है जिनकी गारंटी नहीं दी जाती.

और जिस सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में निर्माता जान-बूझकर ख़ामोश रहते हैं : वह है पिक्चर ट्यूब.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड की गारंटी इसके खरीदारों को ध्यान में रखकर दी जाती है.

बग़ैर किसी संशय के, पूरी तरह बेनुक्स गारंटी. जिसमें पिक्चर ट्यूब भी शामिल होती है.

ऐसी गारंटी जो आपको सुरक्षा देती है... न कि निर्माता को.

पिरामिड में एक ख़ासियत नहीं जो ज़्यादातर दूसरे टी वी में होती हैं : धूल-गर्द.

धूल-गर्द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की सबसे ख़तरनाक दुश्मन है.

बदकिस्मती से ज़्यादातर टी वी जब कारखाने से निकलते है तो इनमें धूल या गर्द मौजूद होती है.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड कारखाने में तकनीकी साफ़-सफ़ाई के सबसे ऊंचे स्तर को कायम रखा जाता है. तभी तो हर पिरामिड टी वी तैयार होता है पूरे धूल नियंत्रित वातावरण में.

पिरामिड : न कोई चिंता, न कोई ग़म इस टी वी में ऐसा दम.

टी वी ख़रीदते समय आपका पहला सवाल यही होता है– "इसके निर्माता कौन हैं?"

और हमारे पास है इसका बहुत ही ठोस और विश्वसनीय जवाब. क्योंकि पिरामिड के निर्माण के पीछे है ६०० करोड़ रुपये की बिक्री का– लालभाई ग्रुप.

बरसों की मेहनत और लगन के बलबूते पर लालभाई ग्रुप ने टेक्सटाइल्स, एअरकंडीशन से, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और फ़ायनान्स के क्षेत्र में ऊंचे दर्जे के उत्पादन तैयार करके अपनी खास पहचान बनाई है.

इसीलिए तो जब आप पिरामिड ख़रीदते है तो आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती.

क्योंकि आपकी तमाम फ़िक्रों का बोझ पहले ही उठा लिया है लालभाई ग्रुप ने.

पिरामिड पेश करते है पिरामिड २००० ई, पिरामिड २००० आर, पिरामिड प्लस (रिमोट और नॉन रिमोट), पिरामिड परफ़ेक्ट और पिरामिड २०९ जे कलर में. पिरामिड १४२, पिरामिड १४५ टी और पिरामिड १४५ ई, १४" ब्लैक एण्ड व्हाइट पोर्टेबुल में, पिरामिड ५१० और पिरामिड ५११ २०" ब्लैक एण्ड व्हाइट में.

पिरॅमिड . . . मग शंकाच नाही.

Regd. Office: Arvind Mills Ltd. (E.D.), Naroda Road, Ahmedabad. Ph: 378165 • 8 Community Centre, Saket, New Delhi. Ph: 663816. • 8th Floor, Shah House, Worli, Bombay. Ph: 4939274.

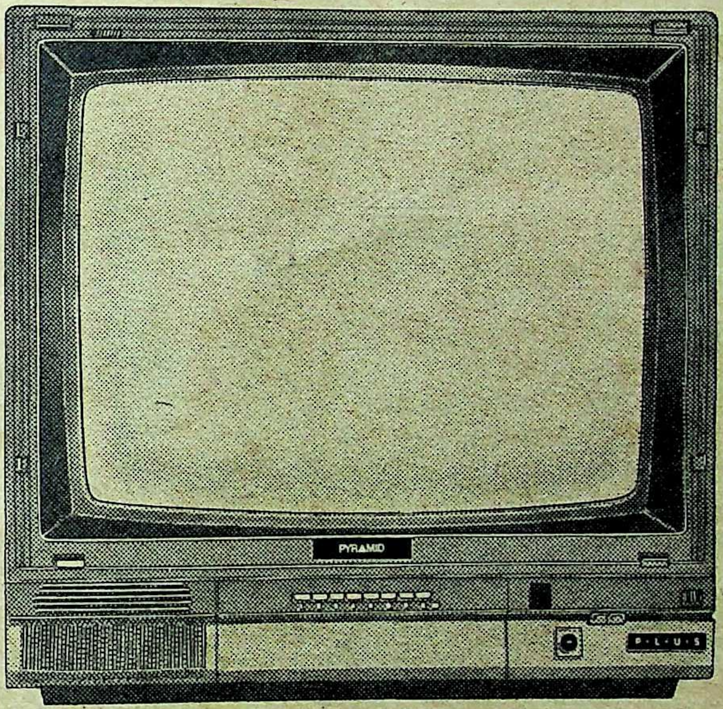
PYRAMID
P·L·U·S

PYRAMID
COLOUR TELEVISION
THE LALBHAI GROUP

जापानी टेक्नालॉजी का उत्पादन.

Trikaya.AMED.12.88.HIN

इलाहाबाद उपचुनाव

राज बब्बर ने ऐसे किया चुनाव-प्रचार

जहां 'रामायण' सीरियल के 'राम' अरुण गोविल अपनी 'राम' की इमेज का प्रभाव इलाहाबाद में कांग्रेस के बुलाने पर भुनाने के लिए आये, वहीं फिल्म अभिनेता राज बब्बर जनमोर्चा के एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से ११ जून को इलाहाबाद पहुंचे। राज बब्बर के आने का न तो ढिंढोरा पीटा गया और न ही उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए अपने ग्लैमर का प्रदर्शन किया। उनका आना गुपचुप ही कहा जायेगा।

जनमोर्चा के गठन के साथ ही राज बब्बर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हो गये थे। कांग्रेस से अलग होने के बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्ट सरकार की काली करतूतों की जानकारी राष्ट्र के नागरिकों को देने की मुहिम चलायी, तो इस महायात्रा में कई स्थानों पर राज बब्बर भी उनके साथ रहे। छात्र जीवन में आगरा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और समाजवादी युवजन सभा के नेता की हैसियत से उन्होंने छात्र हितों के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं, लाठियां खायी थीं और जेल गये थे। जब देश के हित की बात आयी, तो वह इस लड़ाई में भी कूद पड़े।

११ जून को वह इलाहाबाद पहुंचे, तो लोगों को खबर नहीं लग सकी कि इस शहर में राज बब्बर आ गये हैं। पर इलाहाबाद पहुंचते ही वह विवादों में फंस गये। जनमोर्चा के लोगों का कहना था कि यदि राज बब्बर चुनाव प्रचार में कूदते हैं, तो कांग्रेस द्वारा यह प्रचारित किया जायेगा कि 'जनमोर्चा' फिल्मी हस्तियों का सहारा लेकर मतदाताओं को अपनी ओर मोडना चाहती है।

विवाद ने अपना रंग दिखाया। राज बब्बर को स्थानीय एक होटल के कमरा नं० १७ (जहां ठहरे थे) से निकाल कर विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऐश महल (अब 'मांडा कोठी') के एक कमरे में ठहरा दिया गया। जब ऐश महल से संपर्क किया गया, तो बताया गया कि जिस तरह पोस्टर और बैनर कमरों में बंद हैं, उसी तरह राज बब्बर को भी एक कमरे में रखा गया है। लेकिन, यदि अरुण गोविल को इंका प्रत्याशी सुनील शास्त्री के पक्ष में प्रचार के लिए उतारा गया, तो राज बब्बर को भी कमरे से बाहर कर दिया जायेगा।

११ जून की शाम को पीडी टंडन पार्क में विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में विपक्ष की ओर से ऐतिहासिक मीटिंग थी। लोगों को आशंका थी कि विवादों के बावजूद राज बब्बर को इस सभा में बोलने का मौका मिलेगा। सभा हुई, पर राज बब्बर के बिना। यानी कि फिल्मी हस्तियों का उपयोग कांग्रेस करे, तभी जनमोर्चा करेगी—यह साबित हो गया।

महज एक कार्यकर्ता : वीपी सिंह के प्रचार में राजबब्बर

छाया : मनमोहन शर्मा

लाल पद्मधर को माल्यार्पण : पर राज बब्बर कहां मानने वाले थे। ११ जून की दोपहर में ही वह अपने सहयोगियों के साथ ऐश महल के उस कमरे से खिसक लिए और जा पहुंचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छात्रनेताओं से मुलाकात करने के बाद राज बब्बर ने छात्र संघ भवन के सामने स्थित शहीद लाल पद्मधर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए छात्रों से आह्वान किया कि वे वीपी सिंह का समर्थन करें। सत्ता परिवर्तन के लिए आगे आयें।

इस तरह एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से राज बब्बर ने वीपी सिंह के समर्थन में चुनाव-प्रचार का श्रीगणेश किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल कर वह स्वरूपरानी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ३ जून को अल्लापुर में हो रही मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की चुनावी सभा के दौरान मारपीट में घायल हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष को देखा। राज बब्बर की यह सक्रियता आभास दे रही थी कि वह अपने ढंग से चुनाव-प्रचार करेंगे। और उन्होंने ग्लैमरस इमेज और शानोशौकत को ताक पर रखकर घर-घर, दरवाजे-दरवाजे घूमना शुरू किया। नुक्कड़ सभाएं कीं। पैदल और रिक्शे पर चलते राज बब्बर को एकबारगी देखकर बताना मुश्किल था कि यह फिल्म अभिनेता राज बब्बर ही हैं। पहचानते ही लोगों के कदम उनके साथ हो जाते थे। राज बब्बर घर-घर जाकर वोट मांगते रहे। अपने हस्ताक्षर लेने वालों से वह वादा लेते रहे कि वे अपना वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह को ही देंगे।

वीपी सिंह के लिए जन समर्थन जुटाते समय इस संवादाता से बातचीत के दौरान राज बब्बर ने कहा कि पीडी टंडन पार्क में न जाने का मतलब न तो कोई विवाद था और न ही जनमोर्चा ने मना किया था कि मैं चुनाव-प्रचार न करूं। यह सब कांग्रेस का प्रचार है। मैं यहां फिल्मी हस्ती के तौर पर नहीं आया हूं। मैं जनमोर्चा का एक कार्यकर्ता हूं। जैसे अन्य प्रचारक किसी-न-किसी व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं, उसी तरह फिल्मों में काम करना मेरा व्यवसाय है। जब किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति चुनाव-प्रचार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ? मैं भी मेहनती कार्यकर्ता हूं। छात्र जीवन में मैंने छात्र नेता की हैसियत से बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं—छात्र हितों के लिए। मेरे यहां आने का यह मकसद नहीं है कि मैं यहां भीड़ इकट्ठा करूं। अब तक फिल्मी हस्तियों का यह काम रहा है कि वह भीड़ इकट्ठा करेगा और जब भीड़ जुट जायेगी, तो नेता मंच संभाल लेंगे। वीपी सिंह के लिए किसी को भीड़ तो इकट्ठा करने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैं टंडन पार्क की मीटिंग में नहीं गया। मैं जाता तो कांग्रेसी यही प्रचार करते कि भीड़ तो राज बब्बर को देखने आयी थी। राज बब्बर का यह मानना है कि इलाहाबाद का चुनाव आनेवाले वक्त में देश को एक नयी दिशा प्रदान करेगा। राजनीति में एक विशेष परिवर्तन होगा और सामाजिक बदलाव आयेगा।

चुनाव-प्रचार के दौरान घर-घर जाकर वोट मांगते राज बब्बर किसी भी कोने से लोकप्रिय फिल्म अभिनेता होने का आभास तक नहीं होने देते थे। लगता था 'जनमोर्चा' का कोई सक्रिय कार्यकर्ता अपने नेता के लिए काम कर रहा है। तभी तो राज बब्बर ने कहा कि मैं जनमोर्चा का एक कार्यकर्ता हूं—बस।

—दिनेश दीनू

हर सफ़र में हम सफ़र .....

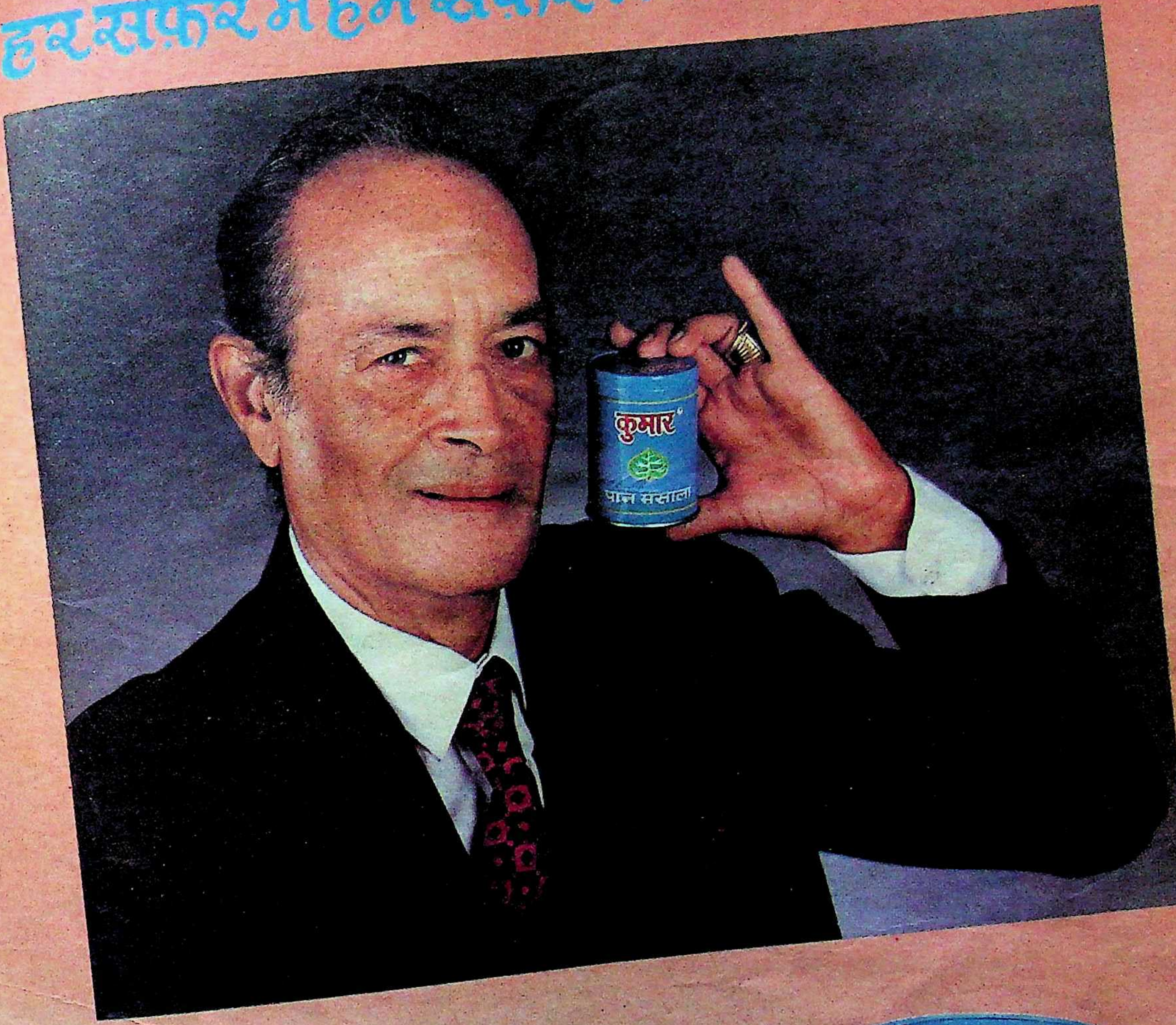

KUMAR
PAN MASALA
कुमार
पान मसाला
कुमार
पान मसाला
जर्दा मिक्स

कुमार®

पान मसाला

निर्माता – **कुमार केमिकल्स**, कानपुर-२०८ ००१

वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

इलाहाबाद उपचुनाव

दूरदर्शनी राम के आने का मतलब

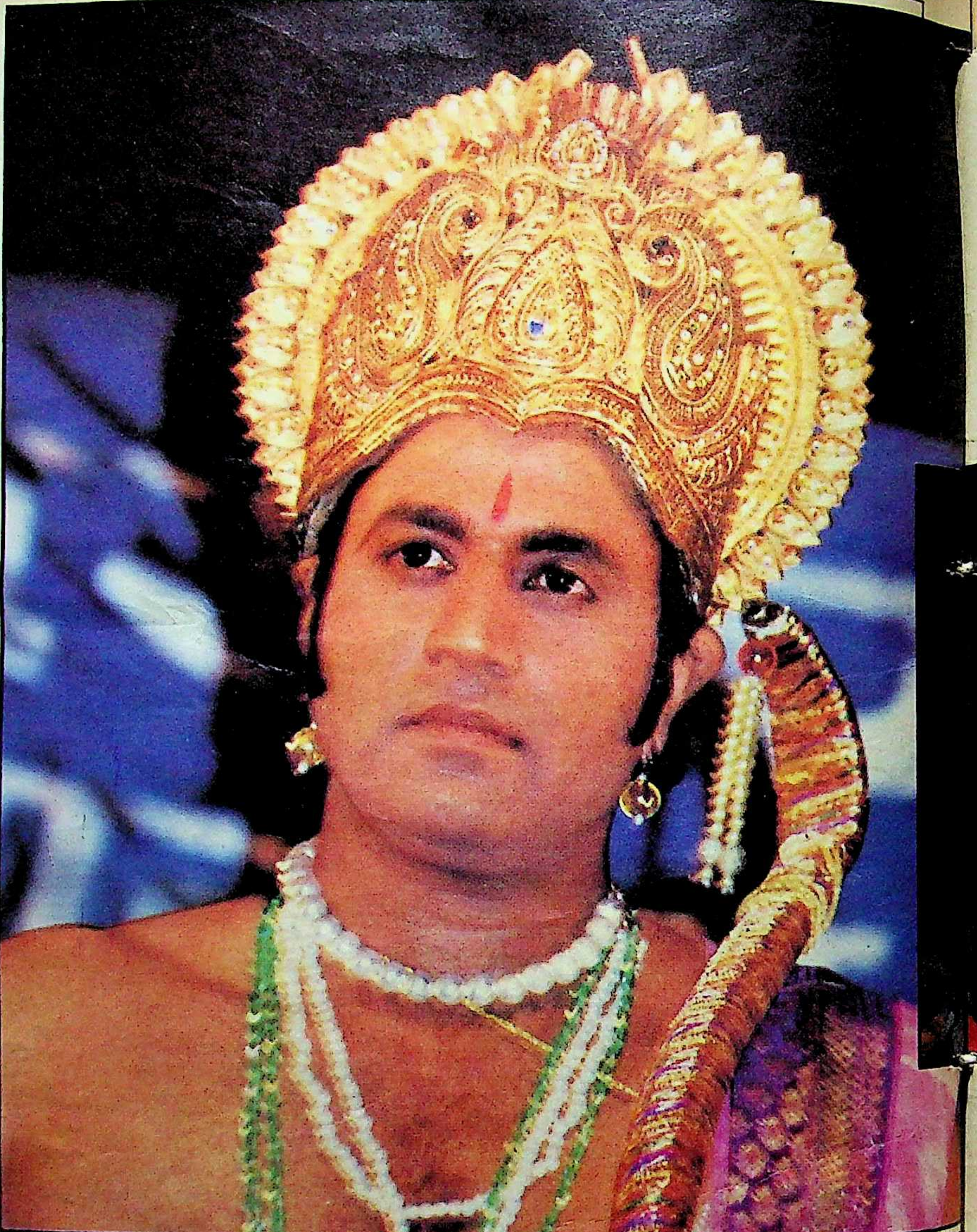

'राम' की माया भी काम नहीं आयी: रामानंदी 'रामायण' के 'राम' (बायें), कांग्रेसी 'राम' (दायें) छाया: नागें 'पंकज'

जब से राजीव गांधी ने कांग्रेस-इ की कमान सभाली है और सत्ता में आये हैं, तब से कांग्रेस-इ का झुकाव फिल्मी हस्तियों की ओर बढ़ा है। १९८४ के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के दिग्गज नेताओं को संसद में पहुंचने न देने की चलायी गयी मुहिम में फिल्मी हस्तियों को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने पहली बार उतारा था। अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और वैजयंती माला सांसद के रूप में संसद में पहुंचे। दरअसल, एमजी रामचंद्रन और नंदमूरि तारक रामाराव जैसी फिल्मी हस्तियों की राजनीतिक सफलताओं से प्रेरित होकर ही कांग्रेस-इ ने १९८४ के लोकसभा चुनाव में फिल्मी कलाकारों का पूरा इस्तेमाल किया था। इस प्रयोग में सफल होने के बाद कांग्रेस-इ ने जनता को अपनी ओर झुकाये रखने के लिए बराबर अवसर आने पर इनका इस्तेमाल जारी रखा। तभी तो राजेश खन्ना और श्रीदेवी के कांग्रेम में आने की चर्चाएं गरम हुईं।

और अब जब इलाहाबाद में कांग्रेस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आयी, तो अपने प्रत्याशी सुनील शास्त्री को विजयी बनवाने के लिए उसने 'रामायण' सीरियल के 'राम' अरुण गोविल को चुनाव प्रचार के लिए १२ जून को इलाहाबाद में उतार दिया। इस खेल के पीछे यह मंशा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इमेज इलाहाबाद की जनता पर प्रभाव डालेगी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले में सुनील शास्त्री आसानी से जीत जायेंगे।

दरअसल, ११ जून को विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में विपक्षी नेताओं की सभा में जो ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी, उससे कांग्रेसी नेताओं के होश फाख्ता हो गये। अरुण गोविल को लाने की कशमकश तो पहले से ही चल रही थी। पर इस सभा के बाद किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये इंका नेताओं को एक यही रास्ता सूझा कि अब 'राम' ही उन्हें बचा पायेंगे। 'राम' को बुलाने की योजना बनी और इसी के साथ यह भी योजना बनी कि जब 'राम' (अरुण गोविल) मंच से जनता से सुनील शास्त्री को जिताने की अपील करें, तभी मंच पर चप्पल-जूते फेंके जायें और प्रचारित किया जाये कि जनमोर्चा के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर जूते-चप्पल फेंककर भगवान राम का अपमान किया है। पर यह योजना लीक हो गयी और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी।

कांग्रेस ने पहले तो कोशिश की कि अमिताभ बच्चन चुनाव प्रचार के लिए आयें। पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर सुनील दत्त को लाने का प्रयास किया गया, पर वह भी आने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल, 'शांति पदयात्रा' के समय कांग्रेस ने उनकी जो उपेक्षा की थी, उससे वह तभी से

कांग्रेस से नाराज हैं। इलाहाबाद न आकर वह जर्मनी चले गये।

इधर इलाहाबाद में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। शुरू में तो इंका के महासचिव गुलाम नबी आजाद फिल्मी कलाकारों को बुलाने के पक्ष में नहीं थे। किंतु प्रचार में लगी 'बुद्धिजीवी' टीम के इस सुझाव को कि 'राम' (अरुण गोविल) को बुलाया जाये, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने मंजूरी दे दी। गुलाम नबी आजाद ने बंबई संपर्क साधा। बीआरसीसी—आई के अध्यक्ष मुरली देवड़ा ने अरुण गोविल से संपर्क साधा और अरुण गोविल चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गये।

१२ जून को पीडी टंडन पार्क में 'रामायण के राम' आ रहे हैं, इसका प्रचार दिनभर शहर में घूम-घूमकर लाउडस्पीकरों से किया गया। लेकिन विपक्ष की ११ जून के मुकाबले में भीड़ पीडी टंडन पार्क में नहीं जुट सकी।

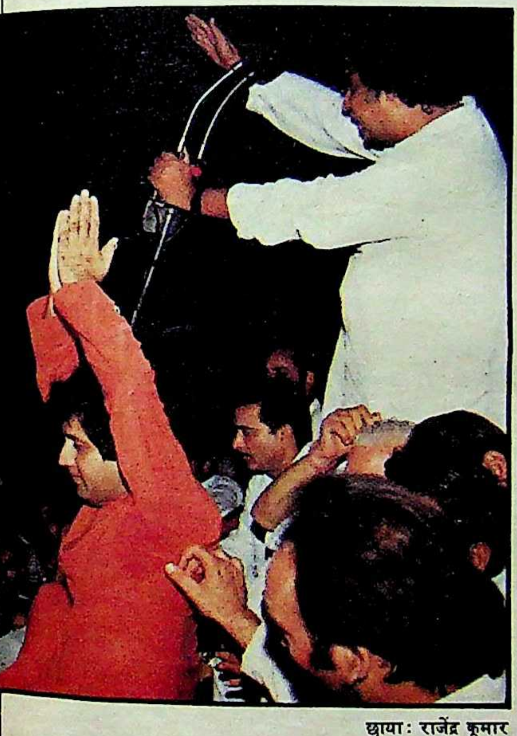

छाया: राजेंद्र कुमार

चित्रकूट का नाटक: अरुण गोविल १२ जून को चित्रकूट पहुंचे। कहते हैं, यह भी हिंदू जनता को रिझाने का उनका एक नाटक था। बहरहाल, उनकी अगवानी करने के लिए खास तौर पर तैनात कुछ लोग इंका कार्यकर्ताओं से भरी दो-तीन बस लेकर चित्रकूट गये। योजना यह थी कि रास्ते भर 'राम' के दर्शन करवाये जायेंगे, पर जब शाम को इंकाई चित्रकूट से 'राम' को लेकर चले, तो कार तेजी से इलाहाबाद की ओर चल पड़ी, क्योंकि अतिशीघ्र टंडन पार्क में उन्हें किसी तरह जुटायी भीड़ को संबोधित करना था।

इधर पीडी टंडन पार्क में यह आलम था कि 'राम' के आने के पूर्व तक जो भी नेता मंच संभालता और भाषण देता, उसे उपस्थित जनता हूट कर देती। शायद अपनी दुर्गति को भांपकर ही कांग्रेसी खजांची सीतारामजी तुरत-फुरत वहां से फूट लिये। फिर भी मंच पर मंचस्थ गुलाम नबी आजाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, ऊर्जा मंत्री प्रमोद तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री केके तिवारी तथा पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी किसी तरह थेथरई करते रहे। हिंदी की राजनीति पर रोटी सेंकने वाले एक नेता तो बराबर ऐलान करते रहे कि रामचंद्रजी को आप किस परिधान में देखना चाहते हैं, रामायण वाली ड्रेस में या साधारण वेश-भूषा में तथा अब बस दस मिनट में ही आने वाले हैं, गऊघाट तक आ चुके हैं। बस अवतरित ही होने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली है—जैसी तमाम उद्घोषणाएं करते रहे। लेकिन भीड़ थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी चुनावी सभा बिहार की रामलीला पार्टी में तब्दील हो गयी थी। किसी तरह निर्धारित समय से ढाई घंटे बाद जब अरुण गोविल गेरुए रंग के चूड़ीदार पाजामा और कुर्ते में सभा स्थल पर पहुंचे, तो कांग्रेसी नेताओं ने 'सियावर रामचंद्र की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिये।

ऐसा दृश्य हो गया जैसे रामलीला शुरू होने के पहले होता है। इस दृश्य पर इस संवाददाता के पास खड़े एक कांग्रेसी नेता ने कह ही दिया कि यह 'कांग्रेसी रामलीला' है। करीब दस मिनट तक सियावर रामचंद्र की जय तथा हनुमानचंद्र की जय और हिंदी-हिंदुस्तान के गगन भेदी नारे लगते रहे। ऐसे नारे तो शायद शिवसेना और आरएसएस के मंच से भी न लगते हों, जो कांग्रेसियों ने लगवा दिये। नारे लगवाने वाले कांग्रेसी नेता को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने खींचकर बिठाने की कोशिश भी की, पर वह नारे लगवाते रहे। उस संचालक नेता ने तब तो और अति कर दी, जब उसने कहा कि एक तरफ श्री रामचंद्रजी हैं और दूसरी तरफ मौलाना राज बब्बर हैं, अब आपको तय करना है कि आप किसका समर्थन करेंगे? मंच पर बैठे नेताओं ने सूंघ लिया था कि ये नारे वोट काटेंगे, पर उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं था। बाद में कुछ इंका नेताओं ने कहा कि नारे लगवाने का काम कांग्रेस के एक गुट ने अपनी योजना के तहत किया, जो सुनील शास्त्री को हराने का मन बना चुका था।

कांग्रेसी दिवालियापन: अरुण गोविल ने जो कुछ मंच से बोला, वह जनता के गले उतरा ही नहीं—यह चुनाव परिणाम ने बता दिया है। वैसे भी १२ जून की पीडी टंडन पार्क के नजारे ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस ने इलाहाबाद के मतदाताओं के दिमाग में सुनील शास्त्री को जिताने के लिए 'राम आपरेशन' किया, वह सफल नहीं हुआ। आश्चर्य है कि १०३ वर्षीय कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं, जो भीड़ इकट्ठा कर पाता। नतीजतन कांग्रेस को मजबूरन दूरदर्शनी 'राम' की शरण में जाना पड़ा। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ हुई। 'राम' का फायदा कांग्रेस को कितना मिला, यह तो चुनाव-परिणाम से जाहिर हो गया है। इतना ही नहीं 'राम' जहां-जहां गये, वहां-वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गयी। गोधरा, ऊधमपुर और इलाहाबाद में उनके चरण पड़े थे, जहां कांग्रेस का बंटाधार हो गया।

अरुण गोविल को प्रचार मैदान में उतारने का लाभ इंका को भले न मिला हो, किंतु विरोधियों को इंका पर सांप्रदायिकता फैलाने और जनता की धार्मिक भावनाओं का शोषण करने का आरोप लगाने का मौका जरूर मिल गया।

लगभग दो वर्ष से जिस शहर का सांप्रदायिक माहौल बहुत अच्छा न हो और सांप्रदायिकता की आग से उभरे पुराने जख्म अभी भरे भी न हों, वहां चुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावनाओं को उभारना कहां तक उचित था? जबकि पहले से ही राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने समूचे राष्ट्र को उद्वेलित कर रखा है। इस विवाद को हल करने के लिए तरह-तरह की अपीलें की जा रही हैं। पर धर्म निरपेक्षता का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस-इ के नेता 'राम बनाम मौलाना' की घोषणा करके कौन-सा खेल खेलना चाहते हैं—यह वही समझ सकते हैं। इस तरह की घोषणा से इलाहाबाद का मुस्लिम मतदाता नाराज ही हुआ। एक तो ईद के मौके पर पानी का न मिलना और दूसरे इस तरह की घोषणाओं से कांग्रेस को मुस्लिम मत नहीं मिले—इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

इससे अधिक विडंबना क्या होगी कि एक तरफ सरकार धार्मिक स्थानों को राजनीतिक उत्सवों और राजनीतिक पार्टियों के लिए बंद रखने के लिए विधेयक जारी कर रही है, नये कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता-पार्टी धार्मिक भावनाओं को उभारकर वोट हथियाने के लिए खुद धर्म की आड़ ले रही है। कांग्रेस-इ नेताओं की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उसने रामानंद सागर की 'रामायण' के 'राम' को नहीं, बल्कि एक फिल्म स्टार अरुण गोविल को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया। अरुण गोविल फिल्मी दुनिया के इतने लोकप्रिय कलाकार नहीं हैं कि जनता उन्हें देखने और सुनने के लिए बेताब हो जाये। उनकी लोकप्रियता का एकमात्र कारण यही है कि वह टीवी सीरियल 'रामायण' में 'राम' की भूमिका कर रहे हैं। भारतीय जनमानस में 'राम' के प्रति अपार श्रद्धा है—इसीलिए कांग्रेस-इ ने अरुण गोविल को नहीं, 'राम' को चुनाव प्रचार में उतारा। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस पार्टी 'राम' को भी अपना औजार समझती है। जो राम मुक्तिदाता हैं, वही राम वोटों की भीख सौगंध दिलाकर मांग रहे थे। देखा जाये तो यह प्रक्रिया संवैधानिक मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन है।

प्रतिक्रियाएं: फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर का कहना है कि अरुण गोविल की इमेज एक फिल्मी कलाकार के रूप में नहीं है। जब तक 'रामायण' टीवी पर है, तभी तक उनकी इमेज की बात हो सकती है। सीरियल खतम होते ही लोग उन्हें भूल जायेंगे। 'हमलोग' और 'बुनियाद' के कलाकार अब क्या कर रहे हैं, किसी को पता है? यह बेकार की बात है कि अरुण गोविल की राम की इमेज है, इसलिए उन्हें किसी का चुनाव प्रचार करना चाहिए। अभिनेत्री भानुप्रिया का तो कहना है कि राम की वेशभूषा में यदि वह जाते, तो अच्छा नहीं

पोस्टर जिसकी धूम रही

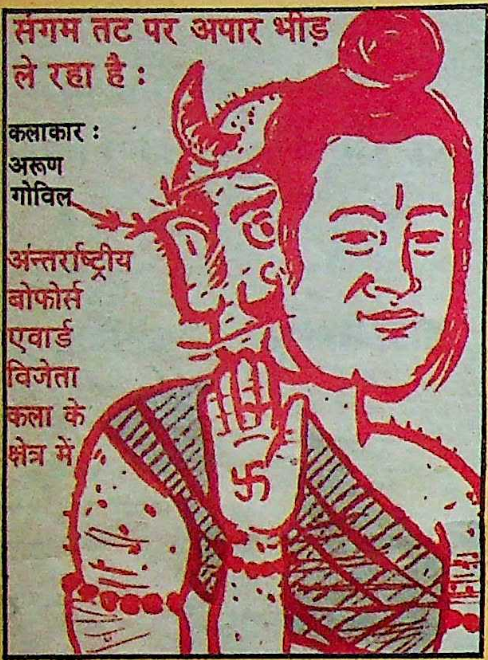
संगम तट पर अपार भीड़ ले रहा है :
कलाकार : अरूण गोविल
अन्तर्राष्ट्रीय बोफोर्स एवार्ड विजेता कला के क्षेत्र में

इलाहाबाद में अरुण गोविल के आने पर एक पोस्टर दीवारों पर लगा जिसमें राम को रावण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस पोस्टर पर जो संवाद, वंदना और गीत अंकित थे, उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :

संवाद

सीता राम से पूछती है ?
हे नाथ, यह कौन है आपके
भेष में चुनाव प्रचार में,
राम सीता से कहते हैं—
सीते, यह रावण है मेरा
भेष बदलकर तेरे समान
पवित्र वोटरों का 'सीता हरण'
करने आया है।

कलियुगी राम की वंदना

ॐ भ्रष्टाचार जननी नमः
ॐ इंका देवी नमः
ॐ इटली पुत्री नमः
ॐ राहुल राजकुमारे नमः
ॐ प्रियंका राजकुमारी नमः
ॐ राम भेष रावणः नमः
ॐ सीता भेष सुर्पणखा नमः
ॐ भ्रष्टाचार अवतारे नमः
ॐ फेयरफैक्स काण्डे नमः
ॐ राष्ट्र द्रोही राजे नमः
ॐ बोफोर्स देवे नमः
ॐ दूरदर्शने चमचे नमः
ॐ लोकतंत्र हत्यारे नमः
ॐ घृणा पात्रे नमः
ॐ पनडुब्बी माता नमः
ॐ कमीशन खोरे नमः
राष्ट्र द्रोही राजे,
त्वमेव माता, च पिता त्वमेव
अतः हे पतित दिल्लीश्वर
स्विस बैंके शरणम् गच्छामि,
इंका भ्रष्ट तंत्रे शरणम् गच्छामि
अहं चाटुकार, अरुण गोविल चमचा अस्तु
त्वमेव स्विस बैंक पति,
दया करो भ्रष्टाधिपति,
एक सीरियल और एक प्रतिशत कमीशन दो
अतः विजयी भव रावण शिरोमणि

कलियुगी रामायण

सतयुग के राम की जय
रामचंद्र कह गये सिया से
ऐसा कलयुग आयेगा
रावण राम का भेष बदलकर
संगम तट पर आयेगा।
चुनाव प्रचार करेगा, तोप दलालों का
चित्रकूट भी जायेगा।
सूर्पणखा सीता का भेष धरेगी,
दूरदर्शन इनके गुण गायेगा।
चिंता मत कर सीते तू
भक्त हमारे बड़े चतुर हैं,
नकली रावण मुंह की खायेगा
एक दिन सतयुग आयेगा
तोप दलाल नरक में जायेगा।

गीत

इंका की यह रीत सदा चली आई,
वोट मिलें देश चाहे भाड़ में जाई।
हिंदु, मुस्लिम और सिख ईसाई,
सबसे इंका करवाये लड़ाई।
फूट डालो और राज करो,
इनकी यह रीत पुरानी है भाई।
अरुण गोविल ने इंका की,
यों साख जमाई।
नीति है न कार्यक्रम,
भांड़ों ने धूम मचाई।।

होता। फिल्मी हस्तियों ने अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में भाग लेने को अपने-अपने नजरिये से देखा है। दिलीप कुमार और श्रीदेवी अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में कोई बुराई नहीं देखते, जबकि बीआर चोपड़ा कहते हैं कि वह उनका खुद का मामला है। उन्होंने जो कुछ किया होगा, सोचकर किया होगा। वह पढ़े-लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। डिंपल कहती हैं कि वह बच्चे नहीं हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी ने भी 'राम' द्वारा कांग्रेस-इ प्रत्याशी के प्रचार को नैतिक दृष्टि से गलत बताया है, जो एक बेबाक सचाई है। उनके इस बयान में काफी वजन है कि राम की भूमिका करने से कोई भगवान नहीं बन जाता और यदि ऐसा होता, तो मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण आदि की भूमिका करनेवाले कलाकारों को लोग देखना तक नही चाहते।

वीपी सिंह ने 'सागर के रामायण' के 'राम' के आने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि जनपद में होनेवाली सैकड़ों रामलीलाओं में राम-लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका निभानेवाले पात्र जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, मेरे चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस के पक्ष में एक 'राम' द्वारा प्रचार करने पर क्या असर होगा ? 'राम' के आने पर शहर में एक ऐसा पोस्टर दीवारों पर लगा, जिसमें राम को रावण के रूप में चित्रित किया गया था और उस पर चुटीले संवाद और गीत लिखे थे। (देखें बाक्स) ये पोस्टर शहर में काफी चर्चित रहे।

अरुण गोविल ने इंका के समर्थन में चुनाव प्रचार क्यों किया ? इस बारे में तरह-तरह की बातें उठती रहीं। जनमोर्चा के लोगों का कहना रहा कि इसके लिए अरुण गोविल को ५ लाख रुपए दिये गये। किसी ने कहा कि २० लाख रुपए मिले हैं। कुछ का कहना था कि उनका भाव इतना ऊंचा नहीं है। वह पांच हजार रुपए प्रति दिन पर आये। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने भेजा है, इस आश्वासन के साथ कि उन्हें मनमोहन देसाई की एक फिल्म का हीरो बनवाकर उनका कैरियर खड़ा कर देंगे। यह भी चर्चा गरम रही कि उन्हें रामानंद सागर ने स्वयं भेजा था, ताकि सरकार से 'मधुर संबंध' बन जाये, क्योंकि मंडी हाउस उनके धारावाहिक 'रामायण' को एक जुलाई से आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रामानंद सागर इसे दीपावली तक यानी नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि दीपावली पर अयोध्या में राम का राज्याभिषेक दिखाकर धारावाहिक का समापन करूंगा।

हमारे बंबई संवाददाता ने जब अरुण गोविल की पत्नी लेखा गोविल से संपर्क किया और इस आरोप के बाबत पूछा कि कहा जाता है कि अरुण गोविल ने चुनाव प्रचार के लिए २० लाख रुपए लिये हैं, तो लेखा गोविल ने कहा कि यह आरोप निराधार है कि कांग्रेस ने अरुण गोविल को चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए २० लाख रुपए या कोई पैसा दिया है। इस आरोप पर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना ने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अरुण गोविल ने कांग्रेस से ५ या २० लाख रुपए चुनाव प्रचार के लिए लिये होंगे।

बहरहाल, कहानी जो भी हो, पर इतना तो है ही कि धर्म निरपेक्षता की खाल ओढ़े कांग्रेस की हार से अरुण गोविल की दूरदर्शनी राम की लोकप्रियता पर प्रश्न चिह्न लग गया है। लेकिन इससे तल्ख है एक राम दर्शक की यह टिप्पणी, "अंत समय में आम आदमी बोलता है, हे राम ! लगता है कांग्रेस का अंतिम समय आ गया है।"

—दिनेश दीनू

विधायक

गये हरिद्वार, खाकर आये मार

दोष रेल-अधिकारियों का: विधायक गोपीनाथ सिंह

बुरे फंसे: विधायक रामानंद यादव

बिहार के तकरीबन २२ विधायकों की टीम विभिन्न प्रांतों में पुस्तकालयों की व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में लखनऊ की ट्रेन पकड़ने हरिद्वार जंक्शन पहुंची, लेकिन वहां रेलकर्मियों ने सभी विधायकों की ऐसी खतरनाक खबर ली कि कई विधायकों को मरहम-पट्टी करवानी पड़ी। आखिर यह हादसा क्यों हुआ?

वह तारीख थी २७ मई और दिन था शुक्रवार। उस दिन आम दिनों की अपेक्षा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बेशुमार भीड़ थी। शाम के साढ़े सात बज चुके थे। प्लेटफार्म नंबर एक पर दस डाउन देहरादून एक्सप्रेस खड़ी थी। यात्रियों की भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरातफरी में थी कि तभी अचानक प्लेटफार्म पर एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। यात्रियों ने देखा कि स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय के सामने भीड़ बढ़ती ही जा रही है और जोर-जोर से शोर-शराबा जारी है। दरअसल, बिहार से गये लगभग २०-२२ विधायक और उनके अन्य अमले-कफले रेलकर्मियों से बहस में उलझे हुए थे।

इसी बीच देहरादून एक्सप्रेस ने एक बार सीटी दी। गाड़ी बस खुलने को हुई कि स्टेशन अधीक्षक के दफ्तर के पास खड़े जत्थे में से कुछ लोग भागे हुए पहुंचे और फौरन ट्रेन का 'हौजपाइप' काट डाला। लिहाजा, ट्रेन रुक गयी। ट्रेन तो रुक गयी पर हरिद्वार जंक्शन की स्थिति बेहद संगीन थी। विधायकों व रेलकर्मियों की गरमागरमी अब मारपीट की सीमा पर पहुंच गयी थी। रेलकर्मी भी बेहद उग्र हो चुके थे और जाने कहां से पलभर में हथौड़ा, लोहे की छड़ें और अन्य औजार से लैस हो चुके थे। पलक झपकते ही बिहारी विधायकों की जमात पर तमाम रेलकर्मी टूट पड़े। फिर तो जिसे जिधर रास्ता मिला, जान लेकर भागा। अधिकांश विधायकों का कुर्ता फटा, चप्पलें भागने के क्रम में छूट गयीं और यहां तक कि कुछेक बुजुर्ग विधायकों की धोती खुलते-खुलते बची।

यों हरिद्वार स्टेशन पर ही नहीं, देश के किसी भी स्टेशन पर गाहे-बगाहे यात्रियों व रेलकर्मियों में हल्की-फुल्की झड़प आम बात है। पर उस दिन एकमुश्त बिहार से गये विधायकों के साथ रेलकर्मियों द्वारा की गयी बदसलूकी ने पूरे रेल-मंत्रालय को परेशान कर दिया। विधायकों के साथ हादसे की खबर जब मुख्यमंत्री निवास में टेलीप्रिंटर पर आयी, तो तत्काल मुख्यमंत्री ने रेलमंत्री माधवराव सिंधिया को दिल्ली फोन मिलवाया, पर दुर्भाग्यवश माधवराव विदेश यात्रा पर थे। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को भी एक आपातकालीन पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि उनके प्रांत में बिहार के विधायकों के संग इस तरह की बदसलूकी क्या उनके शासन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या अतिथियों के संग उनके प्रांत में यही सलूक किया जाता है?

दरअसल, बिहार के विधायकों की यह जमात 'बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति' की ओर से अपने प्रांत से बाहर के पुस्तकालयों की कार्यशैली व स्थिति का अध्ययन करने उत्तर प्रदेश गयी थी। २२ विधायकों की इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे विधानसभा पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष भाजपा विधायक गोपीनाथ सिंह। गोपीनाथ के अलावा विधायकों में एसयूसीआई के विधायक नलिनी रंजन सिंह, इंका विधायक योगेश्वर झा, प्रमोद कुमार सिंह, खलील अंसारी, इन्द्रनाथ भगत और रामदेव सिंह यादव आदि थे। शिमला में पुस्तकालय समिति की बैठक में शरीक होने के बाद इन विधायकों को २८ मई को उत्तर प्रदेश

विधानसभा में होनेवाली एक बैठक में भाग लेना था। इसके लिए विधायकों को हरिद्वार से देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचना था। पर विधायक अपने आरक्षण की स्थिति जानने के लिए जब रेल अधिकारियों से मिले, तो रेल अधिकारियों ने विधायकों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार सहित आरक्षण की संभावनाओं से इनकार कर दिया, जबकि २० मई को ही विधायकों का आरक्षण कराया जा चुका था। पर इसके बावजूद विधायक जगह के लिए परेशान हरिद्वार जंक्शन पर भटक रहे थे। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष विधायक गोपीनाथ सिंह 'माया' से कहते हैं, "एक रेल अधिकारी ने प्रति-टिकट अतिरिक्त रुपए की मांग की। इस बात पर विधायकों से बहस शुरू हुई और रेलकर्मी हिंसा पर उतारू हो गये।" दूसरी ओर रेलकर्मियों ने घटना के बाद तर्क दिया कि ट्रेन में जगह न मिलने पर उत्तेजित विधायकों ने हौजपाइप काटना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने पर विधायकों ने झगड़ा शुरू कर दिया। विधायक गोपीनाथ सिंह रेलकर्मियों के इस आरोप को असत्य बताते हैं। हरिद्वार कांड के बाद विधायको ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को लिखित विबरण दिया कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी इस बदसलूकी के बाद पूरी उदासीनता बरती। हरिद्वार-हादसे के शिकार पटना के विधायक रामानंद यादव 'माया' से कहते हैं, "उस घटना के दूसरे दिन विधायकों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह व रेल उपमंत्री को पूरी आपबीती सुनायी, पर उन पर भी इन बातों का कोई असर नहीं हुआ।" रामानंद कहते हैं कि नियमानुसार ४३ टिकट एक संग खरीदे जाने पर विधायकों के लिए अलग बोगी का इंतजाम किया जाना चाहिए था। पर रेल अधिकारी भला यह क्यों करते? उलटे पूछने पर बुरी तरह उखड़ पड़े।

घायल विधायकों ने इस कांड के संबंध में हरिद्वार स्टेशन के उपाधीक्षक आईपी नागपाल, स्टेशन मास्टर आरपी गुप्ता समेत पांच रेलकर्मियों के विरुद्ध जीआरपी में भादसं की धारा ३६३, ३६५, ३६७ के तहत अपहरण व लूट का मामला वहीं दर्ज करा दिया। दूसरी ओर हरिद्वार के सोलह रेलकर्मियों ने भी जीआरपी में रपट ठोंक दी कि विधायकों ने आठ रेलकर्मियों को पीटकर घायल कर दिया, साथ ही स्टेशन मास्टर के चैम्बर में घुसकर टेलीफोन तोड़ डाले।

बहरहाल, बिहार के पिटे विधायकों ने घोषणा की है कि अगर एक माह के भीतर दोषी-रेलकर्मियों को दंडित नहीं किया गया, तो सभी विधायक संसद के सामने जाकर धरना देंगे और बिहार विधानसभा में विशेषाधिकार का मामला तो उठायेंगे ही। इस पूरे कांड के संबंध में एक राजनीतिक मजाकिये का कहना है कि विधायकों की उस टीम में तो बिहार के रामानंद्र यादव व रामदेव सिंह यादव सरीखे कई बाहुबली विधायक थे, भला ये रेलकर्मियों से मार खाकर मुंह लटकाये चुपचाप आ कैसे गये?

छाया: दीपक कुमार **—कन्हैया लाल शर्मा**

सत्येंद्र नारायण सिंह

छोटे साहब को गुस्सा क्यों आता है?

राजपूतों की उपेक्षा से चिंतित: सत्येंद्र नारायण सिंह

बिहार में राजपूत राजनीति के मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह उर्फ छोटे साहब इंका में अपनी उपेक्षा के कारण क्या अब सचमुच विद्रोह करके रहेंगे? अन्यथा वह वीपी सिंह के संदर्भ से कांग्रेस-इ में राजपूतों की उपेक्षा की बातें क्यों करने लगे हैं?

जो बात पूरे देशभर के कुढ़े हुए दिग्गज कांग्रेस राजपूत नेताओं के हलके में अर्से से गूंज रही थी, वही बात एकदम छिलका छुड़ाकर जब औरंगाबाद के वयोवृद्ध इंका सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह ने जून के पहले सप्ताह में पटना में कही, तो राजनीतिक नौसिखियों को इस रहस्य का परमज्ञान प्राप्त हुआ कि छोटे साहब बस यों ही फोकट में राजपूतों के पोप नहीं कहे जाते हैं। वाकई, इस बूढ़े ठाकुर में जबर्दस्त राजपूती तासीर व [illegible] है। दरअसल, छोटे साहब ने इस बात का बेहिचक खुलासा किया कि कैसे इंका के भीतर सक्रिय एक खास लॉबी वीपी सिंह के इंका से जाने के बाद इस बात का सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है कि अब राजपूत कभी कांग्रेस के भरोसेमंद नहीं हो सकते। केंद्र से लेकर प्रांतीय स्तर तक सरकार में राजपूतों की उपेक्षा की स्थिति को छोटे साहब ने बड़े ही धारदार अंदाज में उठाया, यह कहते हुए कि हालात अगर ऐसे ही रहे, तो राजपूत पूरी तरह कांग्रेस से विमुख हो जायेंगे। छोटे साहब का बस इतना कहना था कि राजनीतिक गली-कूचों में अफवाहों की धूल उड़ने लगी कि क्या इस पकी उम्र में छोटे साहब एक बार फिर कांग्रेस से विद्रोह करने के मूड में आ गये हैं। क्या छोटे साहब कांग्रेस के 'वीर कुंवर सिंह' बनेंगे? ये और ऐसी अनगिनत दिलचस्प अटकलें बिहार के प्रथम वित्तमंत्री स्व० अनुग्रह नारायण सिंह के इकलौते पुत्र छोटे साहब को लेकर पंख मारने लगीं कि इंका में उपेक्षा से आहत बूढ़े ठाकुर साहब अपने लंबे राजनीतिक जीवन का अंतिम दाव अब नहीं खेलेंगे तो भला कब खेलेंगे? जबकि छोटे साहब के आलोचकों ने तुक्का मारा कि छोटे साहब कोई बगावत नहीं करने जा रहे हैं। बल्कि इंका में आने के बाद अपनी ऊंघती-सोती राजनीति को एकबार फिर सुर्खियों में लाने का उनका यह तानाबाना है। पर ऐसा नहीं कि छोटे साहब सिर्फ

जय किसान
मजदूर एकता जिन्दाबाद
5 जून
ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान

अचानक किसान-मजदूरों की चिंता : मंच पर सत्येंद्र नारायण सिंह (बायें से दूसरे)

इंका में राजपूतों के मानमर्दन का सवाल उठाकर ही चुप बैठ गये। मई के मध्य में पटना के चप्पे-चप्पे में 'किसान मजदूर समन्वय समिति' नामक एक नवोदित संगठन का पोस्टर छाया हुआ था। शुरू में लोगों को लगा, संभवतः यह पोस्टर 'मजदूर किसान संग्राम समिति' के नक्सली नेता डा० विनयन के किसी कार्यक्रम से सम्बंधित है। पर नीले रंग के इस पोस्टर पर एक टोपीधारी बुजुर्ग की तस्वीर छपी थी। यह तस्वीर छोटे साहब की थी। इंका की अंदरूनी दुनिया में आश्चर्य मिश्रित आशंका हुई कि कांग्रेस में नक्सली तेवर के नेता डा० जगन्नाथ मिश्र की भांति छोटे साहब भी जंगी-नारा बुलंद करने के मूड में आ गये हैं। छोटे साहब बिहार के नफीसतम राजनेता माने जाते हैं। वही छोटे साहब अचानक किसान मजदूरों के दुख-दर्द से इतने विह्वल क्यों हो गये? यह बात चौंकानेवाली जरूर थी। औरंगाबाद का कई दशक से संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे छोटे साहब के अपने चुनाव क्षेत्र के किसान-मजदूर अब अपने दमन व पिछड़ेपन से हताश होकर हिंसक रास्ते पर उतर पड़े हैं, वहां जाकर कभी उन किसान-मजदूरों की सुधि लेने की फिक्र उन्हें नहीं हुई। पर वही छोटे साहब जब जून के पहले सप्ताह में किसान-मजदूर का अलख जगाते विद्रोही तेवर में उतरे तो राजनीतिक खिलाड़ियों का चौंकना लाजिमी था कि आखिर छोटे साहब को हो क्या गया है?

किसान-मजूदरों का सवाल : बहरहाल, ४-५ जून को पटना के ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉलं में किसान-मजदूर समन्वय समिति के अध्यक्ष की हैसियत से छोटे साहब ने तकलीफ जाहिर की कि किसान व मजदूरों के तनावपूर्ण रिश्ते अहितकर हैं। उन्होंने भूमि सुधार कानून की विफलता और न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियों का दर्दनाक ब्यौरा दिया। सचमुच छोटे साहब के मुंह से भूमि सुधार की बातें बेहद दिलचस्प लगती हैं। छोटे साहब के पास आज भी औरंगाबाद से लेकर वैशाली और सीतामढ़ी में जितनी जमीने हैं, उतनी बिहार में शायद ही किसी राजनेता के पास हों। छोटे साहब को अपनी ससुराल से भी अपार जमीन हासिल हुई। उनकी सांसद पत्नी श्रीमती किशोरी सिन्हा के दादा स्व० अवध बिहारी सिंह व पिता स्व० रामेश्वर सिंह बहुत [illegible] जमींदार थे। श्रीमती किशोरी सिन्हा क[illegible] पिता की एकमात्र संतान थीं, इसलिए अप[illegible] की अकूत भूसंपदा की वह स्वतः मालकिन हो गयीं। छोटे साहब के एक आलोचक का कहना है कि छोटे साहब को भूमि सुधार कार्यक्रम अपनी ही जमीन से शुरू करना चाहिए यानी—'चैरिटी बिगिन्स ऐट होम'। पर छोटे यह 'चैरिटी' शायद ही कभी शुरू करें।

घुटन : आज कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे छोटे साहब का दुख बेमानी नहीं है। शायद कांग्रेस में रहना उनके परिवार के लिए कभी मंगलकारी नहीं हुआ। उनके पिता इस प्रदेश की एक ताकतवर व सम्मानित हस्ती थे। पर कभी सत्ता शीर्ष पर उन्हें जगह नहीं मिली। अपने पिता के जीवनकाल से ही राजनीति में सक्रिय छोटे साहब को भी बहुत जल्दी इस बात का इलहाम हुआ कि श्रीमती गांधी के साथ रहकर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने का। लिहाजा, कांग्रेस विभाजन के बाद छोटे साहब भी श्रीमती गांधी से दरकिनार हो गये और लम्बे समय तक दुख-सुख झेलते विपक्ष की राजनीति में मसरूफ रहे। जनता शासनकाल जब आया, तो छोटे साहब के शुभचिंतकों में यह उम्मीद बंधी कि सत्ता से कई दशकों के बनवासी छोटे साहब को मुख्यमंत्रित्व की बागडोर अब सौंपी जायेगी। पर स्व० कर्पूरी ठाकुर जैसी विपक्षी हस्ती फिर छोटे साहब के आड़े आ

गयी। जनता-युग में ही टूट-फूट के समय छोटे साहब ने हरिजन नेता रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर कर्पूरी ठाकुर को मात दे दी। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद रामसुंदर दास छोटे साहब से पगहा तुड़ाकर अलग हो गये।

स्व० कर्पूरी ठाकुर से मनमुटाव और जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर की बेरुखी ने विपक्षी राजनीति से छोटे साहब का मोहभंग कर दिया। लिहाजा, १९८४ में श्रीमती गांधी की पहल पर छोटे साहब सदल-बल इंका में दाखिल हो गये। पर दुर्भाग्यवश छोटे साहब की राजनीतिक अहमियत समझनेवाली श्रीमती गांधी चल बसीं। फिर राजीव-राज में छाट साहब भला कहां खपते? छोटे साहब राजनीति में बहुत टूटे पर कभी किसी के पांव पर अपनी टोपी नहीं रखी। बिहार में गांधी टोपी की परंपरा को छोटे साहब पूरी मर्यादा से आज तक निभाते आ रहे हैं। एक क्षण के लिए छोटे साहब की तरफ से खड़ा होकर सोचा जाये, तो छोटे साहब का राजनीतिक जीवन बहुत दुखद रहा। जिन दिनों वह पूरी ऊर्जा के साथ कुछ कर सकते थे, उनके वे तमाम सुनहरे राजनीतिक दिन विपक्षी राजनीति के धुएं में तिल-तिलकर समाप्त हो गये और जब वह काफी उम्र होने पर कांग्रेस में आये, तो कांग्रेस की पुरानी राजनीति का अंतिम युग समाप्ति पर था।

पटना के बोरिंग रोड में ऐन सड़क के किनारे ऊंची चहारदीवारी से घिरी एक आलीशान सफेद इमारत है। पटना के राजनीतिक हलकों में इसे 'चितौड़गढ़' कहा जाता है। यह बात बिहार में किंवदंती की तरह रही है कि चुनाव के दिनों में राजपूत वोट किसे पड़ेंगे, यह फरमान छोटे साहब बस छोटी-छोटी पुर्जी लिखकर इलाकों में भेज देते थे। छोटे साहब की पुर्जी चुनाव में रामबाण का काम करती थी। पर सचमुच छोटे साहब ने राजपूतों के लिए क्या किया, इसका हिसाब-किताब अगर खुद छोटे साहब भी करने बैठें, तोउन्हें निराशा हाथ लगेगी। वह सपत्नीक सांसद हैं। बिहार में जब कभी छोटे साहब के कोटे से कोई मंत्री बना, तो सिर्फ उनके अपने भांजे डा० विजय सिंह जो अभी भी आजाद-सरकार में श्रम राज्यमंत्री हैं। छोटे साहब की समधिन माधुरी सिंह भी पूर्णिया से सांसद हैं। छोटे साहब ने अपनी बाद की पीढ़ी में शायद ही किसी राजपूत को राजनीतिक रूप से सींचा हो जो खम ठोंककर कहे कि हां, छोटे साहब ने मुझे बनाया है। आगामी चुनाव में इस बात की जोरों से चर्चा है कि उनके पुत्र निखिल कुमार छोटे साहब की संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और छोटे साहब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहरहाल, छोटे साहब राजनीति में रहें या अलग हो जायें, पर राजनीतिक हाशिये पर हरदम रखे गये इस नाम को यादकर लोग इतना जरूर कहेंगे कि इस भद्र व्यक्ति के साथ राजनीति ने कभी न्याय नहीं किया।

—विकास कुमार झा

छाया: प्रभाकर

गोबिंद नारायण सिंह

राज्यपाल का राइफल-विवाद!

लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हुआ: गोबिंद नारायण

ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल गोबिंद नारायण सिंह अवैध राइफल-रिवाल्वर रखते हैं? गोबिंद नारायण सिंह की अनगिनत राइफलों व रिवाल्वर को लेकर विवाद क्यों उठा हुआ है? क्या इस विवाद के पीछे गोबिंद नारायण सिंह के राजनीतिक दुश्मन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की भूमिका है?

बिहार के राज्यपाल गोबिंद नारायण सिंह के दो खास शौक रहे हैं। एक तो एक-से-एक नयी-पुरानी फाउंटेनपेन जमा करने का और दूसरा देश-विदेश में निर्मित बेशकीमती बंदूकें एकत्र करने का। गोबिंद नारायण ने मिडिल व मैट्रिक की परीक्षा जिस कलम से दी थी, वह भी उनकी कलमों के अजायब-डिब्बे में सुरक्षित है और उसी तरह सोलह नायाब राइफलों के अलावा रिवाल्वर भी मध्यप्रदेश के सतना के तहत उनके निवास रामपुर से लेकर भोपाल व दिल्ली निवास में संभाल कर रखा जाता रहा है। भोपाल निवास में तो गोबिंद नारायण ने बंदूक-राइफलों को रखने के लिए खासतौर से एक स्ट्रांगरूम ही बनवा रखा है। पर कलम तो नहीं, लेकिन बंदूकों के अपने अजूबे शौक के कारण जून के पहले सप्ताह में गोबिंद नारायण अच्छे-खासे पचड़े में पड़ गये। सतना [illegible] भोपाल तक उनके राज[illegible]तिक विरो[illegible]र-शोर से इस प्रचार मुहिम में लग गये कि गोबिंद नारायण के पास सिर्फ लाइसेंसशुदा राइफल या रिवाल्वर का भंडार नहीं, बल्कि ढेर सारे गैरलाइसेंसी हथियार भी हैं।

दरअसल, विवाद की शुरुआत ४ जून को हुई। उस दिन शनिवार था। गोबिंद नारायण सिंह के द्वितीय पुत्र हर्ष सिंह ने रामपुर पुलिस स्टेशन में अपने परिवार की सभी राइफलें व रिवाल्वर एकमुश्त लाकर जमा करवा दिये। हर्ष सिंह सतना के तहत उसी रामपुर बघेल क्षेत्र से दो बार से विधायक होते आ रहे हैं, जहां से स्वयं उनके पिता गोबिंद नारायण सिंह अर्से तक विधायक रहे।

बहरहाल, गोबिंद नारायण सिंह की सोलह राइफलों में से सिर्फ दस पुलिस के पास जमा करायी गयी थीं। इन दस राइफलों में से ३०० बोर और ३३८ बोर की दो राइफलें तथा २२२ प्वाइंट और २२ प्वाइंट की दो राइफलें अमरीका स्टेट निर्मित थीं और ३७५ बोर, २७५ बोर, ४१६ बोर व ३०३ बोर की राइफलें इंगलैण्ड निर्मित थीं। हर्ष सिंह ने ये सभी शस्त्र अपने घर के निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में जमा करने के बाद सतना के जिलाधिकारी से इल्तिजा की कि वे इन शस्त्रों को जिला समाहरणालय के वज्रगृह में सुरक्षित रखवा दें। जिलाधिकारी ने वैसा ही किया। हर्ष ने सतना के जिलाधिकारी को यह बताया कि उनके पिता ने पटना राजभवन से एक विशेषदूत भेजकर उन्हें निर्देश दिया है कि सभी राइफलें व रिवाल्वर सरकार के पास रखवा दिये जायें, क्योंकि इन शस्त्रों के लाइसेंस की अवधि बीत जाने पर फिर से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो

सका है। इधर दूसरी तरफ सतना से लेकर भोपाल के राजनीतिक हलकों में शिगूफा सुलगने लगा कि हर्ष सिंह ने सतना जिला प्रशासन को स्वेच्छा से राइफलें नहीं सौंपीं, बल्कि पुलिस ने जाकर गोबिंद नारायण सिंह के घर से खुद सभी राइफल-रिवाल्वर जब्त किये। रामपुर में सक्रिय 'लोक प्रशिक्षण केंद्र' के संयोजक भागवत सिंह ने सतना के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दे दिया कि गोबिंद नारायण सिंह के रामपुर, भोपाल व दिल्ली निवास पर कई गैरलाइसेंसी राइफलें व रिवाल्वर हैं, जिन्हें छांपा मारकर पुलिस तत्काल जब्त करे।

क्या सचमुच गोबिंद नारायण सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है? गोबिंद नारायण सिंह 'माया' से कहते हैं, "यह सच है कि उनके पास सोलह राइफलें व एक रिवाल्वर है, सबके सब विधिवत लाइसेंस-प्राप्त। पर जब इन राइफलों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने को आयी, तो मैंने कई माह पूर्व मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आचार्य को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लिखा। पर न तो वोरा ने, न ही आचार्य ने मुझे कोई उत्तर दिया। बहुत दिनों तक मैंने इंतजार किया। आखिरकार, मुझे लगा कि बगैर लाइसेंस का नवीनीकरण कराये राइफल-रिवाल्वर रखना उचित नहीं। मुझे लगा कि क्या पता कल को यही आरोप लगा दिया जाये कि मैं अवैध ढंग से शस्त्र रखे हुए हूं। अवैध हथियार रखने की सात साल की सजा भी है भाई। सो मैंने हर्ष को कहा कि सभी राइफल-रिवाल्वर सरकार के पास जमा करवा दो। मेरे पांच लड़के व एक लड़की है। कानूनन एक व्यक्ति को तीन शस्त्र रखने का लाइसेंस मिल सकता है। इसलिए अपने छहों बच्चों में मैं तीन-तीन बांट दूंगा। अगर सरकार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करती है, तब तो कोई बात ही नहीं।"

क्या गोबिंद नारायण सिंह ने इस आशंका से परेशान होकर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुके अपनी तमाम राइफलों व रिवाल्वरों को सतना जिला प्रशासन के पास इसलिए जमा करवा दिया कि कहीं उनके राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बगैर लाइसेंस नवीनीकरण के राइफल रखने के आरोप में उन्हें किसी भारी पेंच में न फंसा दें। यों अर्जुन सिंह लॉबी ने इस मसले को जबर्दस्त हवा दी भी है। १० जून को गहराते विवाद से क्षुब्ध गोबिंद नारायण सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव सिंहदेव व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्य सचिव ने लाइसेंस नवीनीकरण के उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहरहाल, गोबिंद नारायण सिंह के इस बंदूक-विवाद पर अर्जुन सिंह का रुख क्या है, यह तो इसी से जाहिर होगा कि गोबिंद नारायण सिंह के पूरे राइफल-भंडार में जमा अनगिनत राइफलों व रिवाल्वरों के लाइसेंस के नवीनीकरण का आदेश अर्जुन सिंह की सरकार देती है या नहीं।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

जमशेदपुर के इंका सांसद गोपेश्वर

क्या सांसद ने ३५ लाख का घपला किया?

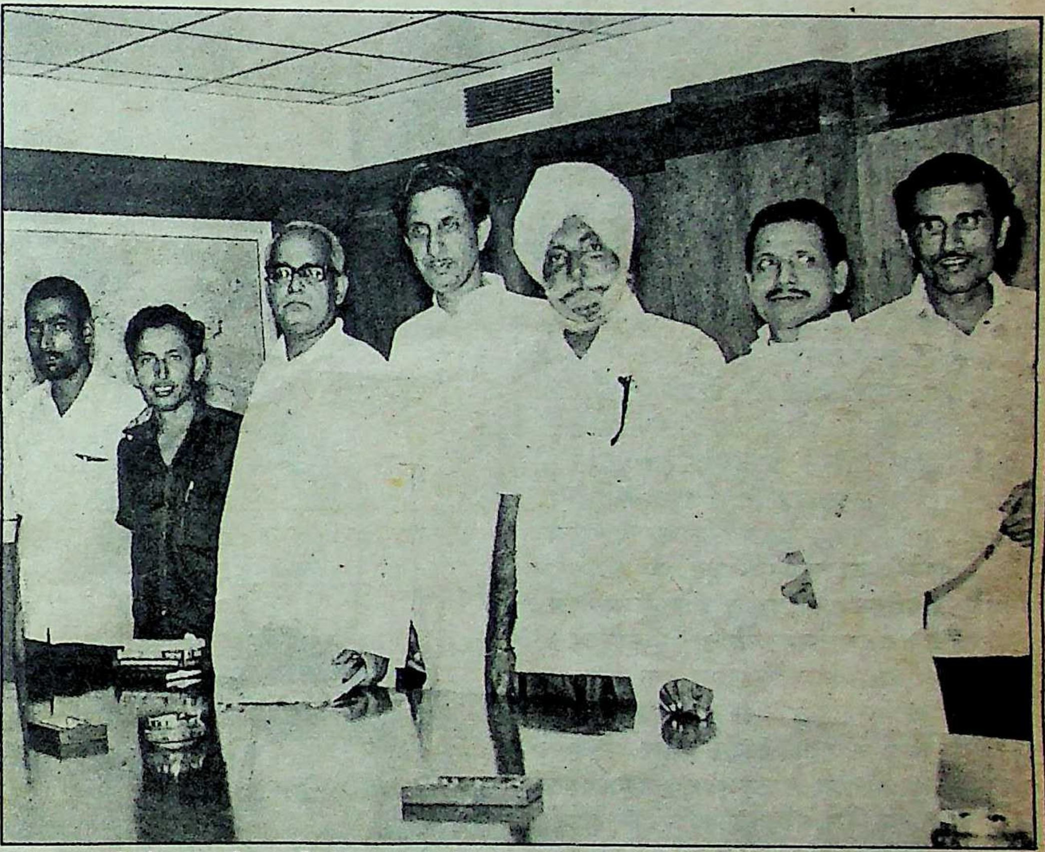

घपले का अभियोग: जमशेदपुर के इंका सांसद गोपेश्वर (बायें से तीसरे)

जमशेदपुर के टेल्को मजदूर यूनियन के कामगार जमशेदपुर के इंका सांसद और टेल्को मजदूर यूनियन के महामंत्री गोपेश्वर के खिलाफ यूनियन कोष से ३५ लाख के घपले की कैसी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं?

जमशेदपुर के इंका सांसद गोपेश्वर पुराने मजदूर नेता हैं और कांग्रेस के मजदूर संगठन 'राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस' (इंटक) के अभी दो माह पूर्व हुए शिमला के सम्मेलन में इंटक के राष्ट्रीय महासचिव भी चुने गये हैं। पर इंटक से ही संबद्ध गोपेश्वर के अपने चुनाव क्षेत्र जमशेदपुर स्थित 'टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी' (टेल्को) की मजदूर यूनियन की कार्यकारिणी के सदस्यों ने [illegible]पेश्वर पर टेल्को मजदूर यूनियन के कोष से ३५ लाख [illegible] के घोटाले का एक संगीन मामला ([illegible]/१, केस नंबर-२३/८७) जमशेदपुर के एडी[illegible]जेएम की अदालत में धारा ४०६, [illegible] ४६५, ४६७ और ४६८ के तहत दायर कर रखा है। गोपेश्वर टेल्को मजदूर यूनियन के १९७० से ही महामंत्री हैं। इस मामले में सांसद गोपेश्वर सहित टेल्को मजदूर यूनियन के पूर्व कोषाध्यक्ष शिशुपाल सिंह और वर्तमान कोषाध्यक्ष प्रशांत मुखर्जी का भी नाम है। गोपेश्वर व पूर्व तथा वर्तमान कोषाध्यक्ष पर यूनियन कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य कुंवर प्रताप सिंह ने ११ मई, १९८७ को ही केस दायर किया था। जमशेदपुर के एडीशनल सीजेएम ने धारा ४२० व ४०६ के तहत कागनिजंस (कानूनी अधिकार के अनुसार) लेते हुए तीनों सज्जनों के नाम सम्मन भी जारी कर दिये और जमशेदपुर के एसडीएम एसआर महतो की अदालत में मामले को निपटाने के लिए भेज दिया। गोपेश्वर की ओर से इस मामले को क्वैश (समाप्त) कराने की अपील उच्च न्यायालय के रांची बेंच में की गयी। १४ दिसंबर, १९८७ को इस मामले में अंतरिम स्थगन आदेश देते हुए रांची बेंच की अदालत ने कहा कि 'क्वैश पेटीशन' के पूरी तरह निपटारे तक नीचे की अदालत की कार्रवाई स्थगित रहे। क्वैश पेटीशन का मामला अभी तक निपटा भी नहीं था कि फिर कुंवर प्रताप सिंह ने रांची बेंच में ही

६ मई, १९८८ को गोपेश्वर द्वारा भविष्य में यूनियन कोष के दुरुपयोग को रोके जाने की प्रार्थना करते हुए एक अपील की। पर बीच में ग्रीष्मावकाश के कारण अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

कुंवर प्रताप सिंह 'माया' से कहते हैं, "टेल्को मजदूर किसी तरह गोपेश्वर से मुक्ति चाहते हैं। यूनियन में महासचिव के पद पर रहकर सिर्फ उन्होंने अब तक टेल्को मजदूरों के हित से खिलवाड़ ही किया है। आखिर मजदूरों के पैसे का हिसाब देने में उन्हें बुखार क्यों चढ़ रहा है?"

पृष्ठभूमि: टाटा लोकोमोटिब इंजीनियरिंग कंपनी (टेल्को) की स्थापना जमशेदपुर में १९४६ में हुई थी। शुरू में यहां वाईजी और वाईपी मॉडल का छोटी लाइन का मीटर गेज इंजन बनता था। फिर १९५४ में जर्मनी की एक कंपनी डेमलर बेंज के सहयोग से यहां बेंज ट्रक और टाटा मर्सीडीज आदि बनने शुरू हुए। फिलहाल, टेल्को में अधिकारी स्तर के लोगों को छोड़कर १८,८४१ कामगार हैं। कई दशक से टेल्को मजदूरों के बीच इंटक से सम्बद्ध यूनियन ही कार्यरत है और टेल्को प्रबंधन द्वारा भी इंटक की ही यूनियन को मान्यता दी गयी है। पहले 'टेल्को मजदूर यूनियन' के अध्यक्ष हुआ करते थे, जमशेदपुर के दिग्गज इंटक मजदूर नेता स्व० माइकल जान। १९६९ में जब टेल्को में एक बार पूरे ४८ दिनों की लंबी हड़ताल हुई, तो तत्कालीन यूनियन अध्यक्ष स्व० माइकल जान ने उस समय यूनियन के महामंत्री रामनरेश को हटाकर १९७० में गोपेश्वर को महामंत्री बनाया। गोपेश्वर उन दिनों वर्णपुर स्थित इस्को कारखाने में मजदूरों की नेतागिरी किया करते थे। टेल्को मजदूर यूनियन में महामंत्री पद पर गोपेश्वर को लाकर माइकल जान ने मजदूर राजनीति में गोपेश्वर की हैसियत रातोरात बढ़ा दी।

टेल्को के कामगारों का कहना है कि माइकल जान जब तक जीवित रहे और टेल्को मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे, तब तक तो गोपेश्वर लक्ष्मण रेखा के भीतर रहे। पर माइकल जान की मृत्यु के बाद टेल्को मजदूर यूनियन को उन्होंने अपना जेबी संगठन बना डाला। १९७० के पूर्व कामगारों से यूनियन के लिए चंदा संग्रह सीधे यूनियन की ओर से रसीद के जरिये किया जाता था। पर १९७३ में एक समझौते के तहत यह तय हुआ कि सभी कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह यूनियन की एक रुपए चंदा राशि टेल्को कंपनी ही काट कर पूरी राशि टेल्को मजदूर यूनियन के बैंक-खाते में जमा करा दिया करेगी। तब से आज तक चंदा संकलन की यही परंपरा जारी है।

गोपेश्वर की मनमानी: बहरहाल, माइकल जान के निधन के बाद उपाध्यक्ष के रूप में गोपेश्वर ने अचानक दिल्ली के एक मजदूर नेता एसएल पाशी को मनोनीत कर दिया, जबकि पाशी का चेहरा भी कभी टेल्को मजदूरों ने आज तक नहीं देखा था। टेल्को मजदरों का कहना है कि यहीं से गोपेश्वर की यूनियन में मनमानी शुरू हुई। यूनियन कार्यकारिणी के सदस्य कमलेश्वर सिंह कहते हैं कि तकरीबन चार वर्षों तक एसएल पाशी उपाध्यक्ष के पद पर ही रहे और टेल्को मजदूर यूनियन मजदूरों के काफी प्रतिरोध के बावजूद बगैर अध्यक्ष के चलता रहा। पर १९८१ में टेल्को प्रबंधन से जब समझौते का मौका आया, तो एक विधिवत अध्यक्ष की आवश्यकता आ पड़ी। लिहाजा, एसएल पाशी गोपेश्वर द्वारा अध्यक्ष पद पर प्रोन्नत कर दिये गये। १९८२ से ही टेल्को मजदूर गोपेश्वर से विधिवत यूनियन का चुनाव करवाने की मांग करते रहे, साथ ही यूनियन कोष का हिसाब भी देने को कहा। पर इसी बीच १९८४ के संसदीय चुनाव में गोपेश्वर जमशेदपुर से इंका का टिकट पाकर कांग्रेस लहर में जीतकर सांसद हो गये। टेल्को मजदूरों के अनुसार सांसद बनते ही गोपेश्वर अब और निश्चित हो गये कि टेल्को मजदूर अब भला उनका विरोध करके भी क्या कर सकेंगे। पर मजदूरों द्वारा फिर [illegible] की हंगामा करने के बाद १९८५ के सित[illegible] में गोपेश्वर ने टेल्को मजदूर यूनियन का [illegible] किया। टेल्को मजदूरों का कहना है कि वह चुनाव बस दिखावा था। गोपेश्वर ने फिर यूनियन पर मजदूरों के तमाम विरोध के बावजूद कब्जा जमा लिया। १९८५ के उस चुनाव के विरोध में उस समय यूनियन के एक सदस्य पशुपति पांडेय ने जमशेदपुर के मुंसिफ कोर्ट में एक मामला (टाइटिल शूट नंबर १३४/८५) भी दायर कर दिया था। यह मामला अभी तक चल ही रहा है। इस नये चुनाव में मजदूरों के विरोध के बावजूद स्वयंभू महासचिव बने गोपेश्वर को विशेष ताकत की जरूरत थी। लिहाजा, गोपेश्वर ने उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे को यूनियन का अध्यक्ष घोषित कर दिया। साथ ही एक उपाध्यक्ष बन गये रवीन्द्र प्रताप सिंह। इधर बिन्देश्वरी दुबे कानून मंत्री बनते ही अध्यक्ष पद से मुक्त हो गये। सो, फिलहाल टेल्को कामगार इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अभी उनकी यूनियन का अध्यक्ष कौन है। टेल्को मजदूरों का कहना है कि अभी की स्थिति में गोपेश्वर टेल्को परिसर में पांव तक नहीं रख सकते, क्योंकि मजदूरों में उनके प्रति भयंकर आक्रोश है। इस वर्ष सिर्फ २ फरवरी को गोपेश्वर एक बार यूनियन के उपाध्यक्ष रामाधार सिंह के नेतृत्व में गोपेश्वर का कड़ा विरोध हुआ। नतीजतन, गोपेश्वर को तत्काल यूनियन दफ्तर से निकलने को विवश होना पड़ा। यों, गोपेश्वर के कुछ समर्थकों का तर्क है कि मजदूर यूनियन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंटक में रहकर भाजपा की राजनीति करते हैं और बेवजह गोपेश्वर के पीछे लगे रहते हैं। पर गोपेश्वर से अपनी नाराजगी के अनगिनत कारण गिनाते हुए टेल्को मजदूर कहते हैं कि प्रबंधन से मिलकर गोपेश्वर ने निजी लाभ में कामगारों के हित का बेहिसाब हनन किया है। टेल्को में यह परंपरा चली चली आ रही थी कि नौकरी की अवधि में किसी कर्मचारी का निधन होने पर उसके आश्रित को यहां नौकरी मिलती थी। पर अब यह बस एक सपना है। टेल्को कामगारों के मुताबिक यूनियन के दो सदस्य गोपाल सिंह व उपेन्द्र सिंह विगत डेढ़ साल से निलंबित हैं, पर गोपेश्वर ने कभी निलंबित कर्मचारी के साथ हुए अन्याय का मामला प्रबंधन के पास नहीं उठाया। मजदूरों का कहना है कि बोनस में भी बहुत घालमेल प्रबंधन ने किया। पर जब यूनियन के महामंत्री ही प्रबंधन से मिले हैं, तो क्या किया जा सकता है।

बहरहाल, टेल्को मजदूरों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक लंबा ज्ञापन भेजा है और कहा है कि कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक का राष्ट्रीय महासचिव जिन्हें बनाया गया है, उन्होंने टेल्को मजदूरों के साथ क्या सलूक किया है? यूनियन कार्यकारिणी के सदस्य और गोपेश्वर पर यूनियन की ३५ लाख की राशि में घपला करने के आरोप सहित अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे कुंवर प्रताप सिंह कहते हैं, "टेल्को मजदूर अदालत से तो न्याय मांग ही रहे हैं। पर प्रधानमंत्री से भी न्याय की फरियाद करते हैं।"

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

कुंवर प्रताप सिंह

कमलेश्वर सिंह

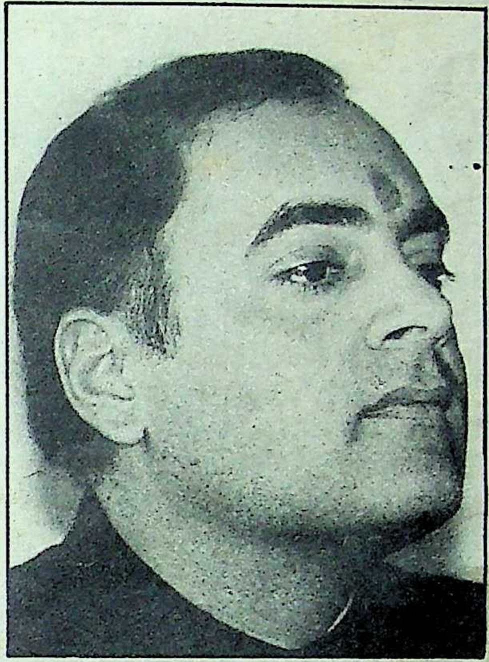
राजीव गांधी

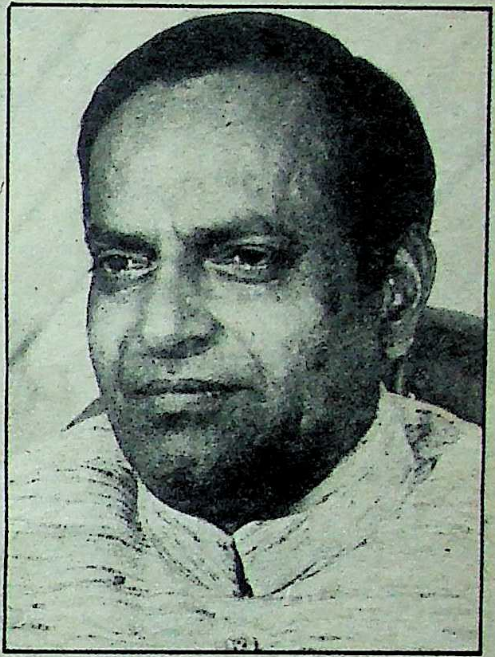
वीर बहादुर सिंह

पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत भेड़ों की नस्ल में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उच्चकोटि की ऊन का उत्पादन हो सके।

इस समय प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में १४ भेड़ फार्म कार्यरत हैं, जिनमें ४.०८ हजार भेड़ें हैं। इन फार्मों के माध्यम से भेड़ पालकों को भेड़ें उपलब्ध करायी जाती हैं। इस समय प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ११३ भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र हैं। अतः ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास किया जा रहा है।

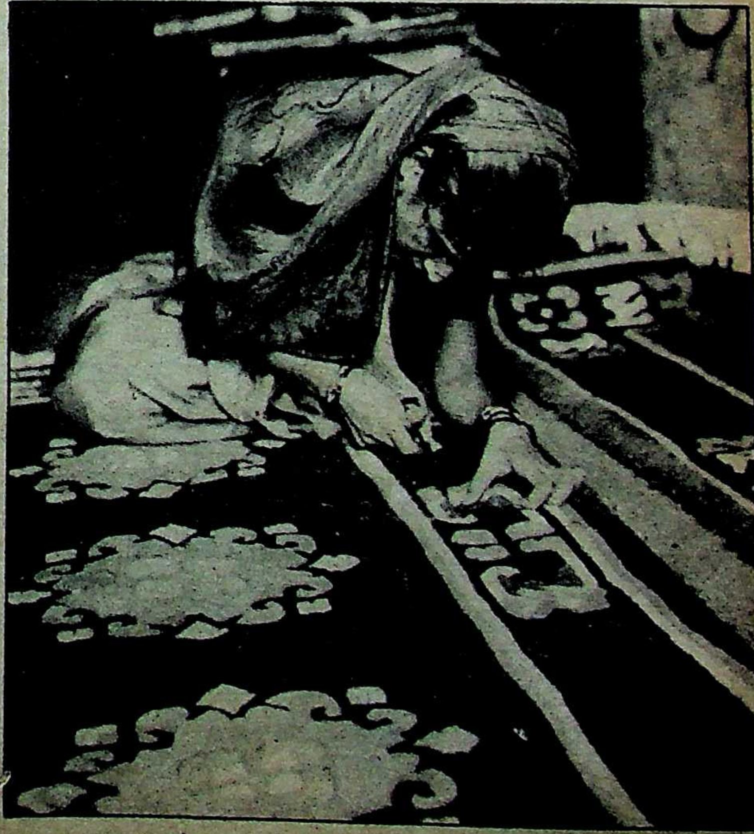
पर्वतीय क्षेत्र में ऊनी गलीचा उद्योग

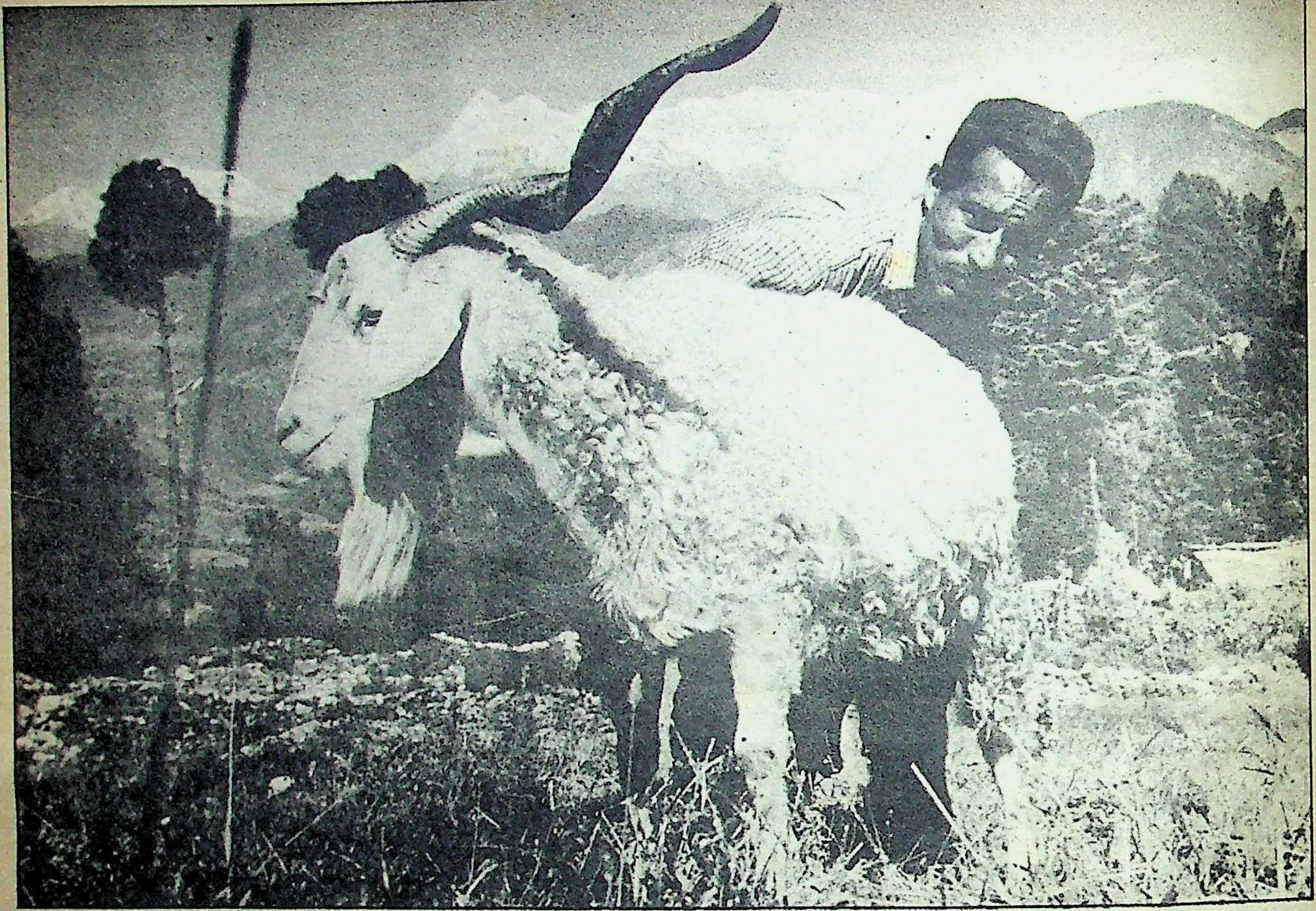

पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस वर्ष १७.६३ लाख रुपयों की व्यवस्था की है। गत वर्ष इस कार्य के लिए १४.८२ लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी थी।

पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ों की कुल संख्या लगभग चार लाख है, जिनसे ऊन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष १९८४-८५ में पर्वतीय क्षेत्र में ३.८० लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ। वर्ष १९८५-८६ में ४.१४ लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ। चालू वर्ष में भी ऊन के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने की संभावना है।

जो भेड़ पालक अपने पास २५ से ५० तक भेड़ें रखते हैं उनको शीप ब्रीडिंग सीजन में सरकारी फार्म से भेड़ें दी जाती हैं, जो ब्रीडिंग के उपरांत वापस कर दी जाती हैं।

भेड़ पालकों से हिल डेवलमेंट आर्गनाइजेशन ऊन खरीदता है और ऊन की बिक्री उन संस्थाओं को करता है, जिनको ऊन की आवश्यकता होती है।

पर्वतीय क्षेत्र में महीन व लंबे रेशे की ऊन पैदा करने के लिए विदेशी एवं संकर भेड़ों का उपयोग किया जा रहा है। चमोली जनपद में मक्कू नामक स्थान पर एक भेड़ प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है, जहां पर रेम्बुले नस्ल की विदेशी भेड़ें रखी गयी हैं। वर्ष १९८४-८५ में ३०० रेम्बुले भेड़ों का आयात किया गया था और अतिरिक्त भेड़ों का आयात भी विचाराधीन है।

ऊन के वर्गीकरण एवं क्रय-विक्रय हेतु प्रदेश में तीन केंद्र कार्यरत हैं, जहां भेड़ पालकों की सहकारी समितियां भी गठित की गयी हैं। अच्छे ऊन एवं फर उत्पादन हेतु अंगोरा खरगोश फार्म की स्थापना भी पर्वतीय क्षेत्र में की जा रही है। सातवीं योजना में तीन अतिरिक्त फार्म गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में खोले जायेंगे।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊन उपलब्ध हो रही है वह 'मीडियम फाइन' श्रेणी में आती है। इस ऊन से पट्टू, कम्बल तथा शाल बनाये जाते हैं। प्रयास है कि ऊन का अधिक-से-अधिक उत्पादन हो। स्थानीय भेड़ों की ऊन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पौड़ी जनपद में एक सघन भेड़ विकास परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की भेड़ें भेड़पालकों को वितरित की जा रही हैं, ताकि भेड़ों के इस संकर प्रजनन कार्यक्रम से स्थानीय भेड़ों को ऊन के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ों व अन्य पशुओं की बीमारियों से बचाने के लिए इस समय २०० पशुचिकित्सालय ५६५ पशुसेवा केंद्र, २ अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र एवं तरल नत्रजन संयंत्र, ११३ भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र, १४ भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं।

सातवीं योजना काल में ७५ नये पशुचिकित्सालय तथा १५० पशु सेवा केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य है, जिनमें से वर्ष १९८६-८७ में २० पशु चिकित्सालय तथा ३२ पशु सेवा केंद्र स्थापित किये गये। इसके अलावा इसी अवधि में २५ नये नैसर्गिक अभिजनन केंद्रों के साथ-साथ ६ नये भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्रों की स्थापना भी की गयी।

चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुधन एवं भेंड़-प्रक्षेत्रों पर चारा-बजि, सीड़, सैप्लिंग तथा चारा नर्सरी का विकास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक सिंचाई सुविधाएं देने की व्यस्था है।

थारू जनजाति का विकास

उत्तर प्रदेश में कृषक-कल्याण योजनाएं तथा कृषि विकास

प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए शासन स्तर पर अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की गयी हैं, जिनसे किसान भाई भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ष शताब्दी के भयंकर सूखे के कारण खरीफ के उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। किंतु फिर भी हमने इतना अन्न उगाया कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ-साथ देश के अन्य भागों को भी अनाज भेजा गया। खरीफ की कमी की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार तथा प्रदेश शासन की ओर से कृषकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

भारत सरकार की ओर से प्रदेश को सुलभ कराये गये २० करोड़ रु० का उपयोग सूखा सहायता तथा १.७० करोड़ रु० का उपयोग बाढ़ सहायता के लिए किया गया है। स्वीकृत धनराशि के माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों को क्रमशः २५ तथा ३३.७५ प्रतिशत की दर से फासफेटिक, पोटेशिक एवं नत्रजन उर्वरकों पर अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, जिसकी अधिकतम सीमा आनुपातिक आधार पर ४० रु० प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। अनुदान की सुविधा पूर्व में ३१ दिसंबर, १९८७ तक ही अनुमन्य थी, किंतु अब इसे फरवरी १९८८ तक बढ़ा दिया गया है। सभी कृषि निवेशों की सामयिक आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों व संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है। आशा है कि किसान भाइयों के प्रयासों से वर्तमान रबी में, १९७ लाख टन खाद्यान्न एवं १५ लाख टन तिलहन का उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, जिससे कुछ सीमा तक खरीफ में हुई कमी की प्रतिपूर्ति हो सकेगी।

सहकारी गोदाम

इस वर्ष कृषि उत्पादन में संभावित कमी को आगामी वर्ष १६८८-८६ में प्रतिपूर्ति के लिए अभी से एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी जा रही है। भारत सरकार के स्तर पर अभी हाल में हुए विचार-विमर्श के अनुसार वर्ष १६८८-८६ के लिए ३५५ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा १५ लाख मेट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित २१ जनपदों में दलहनी फसलों (उरद, अरहर, चना, मटर तथा मसूर) के बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किये जा रहे हैं। परियोजना क्षेत्र के जनपदों में बीज योजना पर १५० रु० प्रति कुंतल की दर से प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान तथा बीज उत्पादन संस्थाओं को ७० रु० प्रति कुंतल की दर से ट्रांस्पोर्टेशन, हैंडलिंग एवं स्टाकिंग पर कृषि निवेश के रूप में अनुदान की सुविधा है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में लघु तथा सीमांत कृषकों के लिए प्रत्येक विशेष किट का बीज मैदानी क्षेत्र में आधा एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चौथाई एकड़ के लिए है। मैदानी क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा चना, मटर प्रत्येक १२ कि०ग्रा० तथा मसूर ८ कि०ग्रा० और पर्वतीय क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा मैदानी क्षेत्रों में देय बीज की आधी होगी। दलहनी फसलों, जैसे अरहर तथा चना को फली क्षेदक कीट से बचाने के लिए २० रु० हेक्टेयर की दर से कृषकों को कृषि निवेश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराये जाने की सुविधा है। दलहनी फसलों में संस्तुत समस्त पद्धतियों के प्रचार हेतु ५० हे० आकार के ब्लाक प्रदर्शन कृषकों के खेतों पर कराने हेतु उन्हें निःशुल्क कृषि निवेश उपलब्ध कराये जाने की सुविधा है। यह अनुदान उरद, मूंग तथा अरहर की फसल पर ६२५ रु०, चना तथा मटर के लिए ८७० रु० और मसूर के लिए ७६०' रु० प्रति हे० तक की सीमा के लिए देय है।

राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चयनित २१ जनपदों में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, रांई, राई/सरसों तथा अलसी के सामान्य बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में राई/सरसों के विशेष बीज मिनीकिट की राइजोबियम कलचर के पैकेट सहित लघु एवं सीमांत कृषकों को। रु० के नगण्य मूल्य पर निःशुल्क वितरित किये जा रहे हैं। ये बीज मिनी किट मैदानी क्षेत्रों के लिए आधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चौथाई एकड़ के लिए होंगे।

विभिन्न तिलहनी फसलों के तहत प्रदर्शन मैदानी क्षेत्रों में ५० हेक्टेयर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में १० हेक्टेयर में अधिकतम ५० प्रतिशत कृषि निवेश अनुदान के रूप में मूंगफली पर १००० रु०; सोयाबीन पर ७०० रु०, तिल पर ३०० रु०, राई/सरसों पर ६०० रु० तथा अलसी पर ४०० रु० प्रति हे० की दर से अनुमन्य है।

कृषि रक्षा उपकरण के मूल्य पर ५० प्रतिशत या अधिकतम ४०० रु० प्रति उपकरण की दर से अनुदान देय है। सोयाबीन के प्रमाणित बीज पर २०० रु० प्रति कुंतल तथा ट्रूथफुल बीज पर १५० रु० प्रति कुंतल की दर से अनुदान देय है। मूंगफली एवं सोयाबीन के प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर १५० रु० प्रति कुंतल अनुदान देय है।

प्रदेश के चयनित २४ जनपदों के १०२ विकास खंडों में केंद्र पुरोनिर्धारित चावल उत्पादन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यन्त्र, संहत क्षेत्रों में निःशुल्क फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं दृश्य दर्शन तथा जलनिकासी की सुविधाएं प्रदान की गयी है।

कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना द्वारा बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा तथा कानपुर में कपास की फसल पर लगने वाले कीट रोगों के उपचार हेतु कीटनाशक दवाओं के मूल्य पर ५० प्रतिशत का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त, पर्वतीय क्षेत्रों में भी कृषि रक्षा कार्यों के हेतु किसी को सभी प्रकार के कृषि रक्षा उपचार के लिए

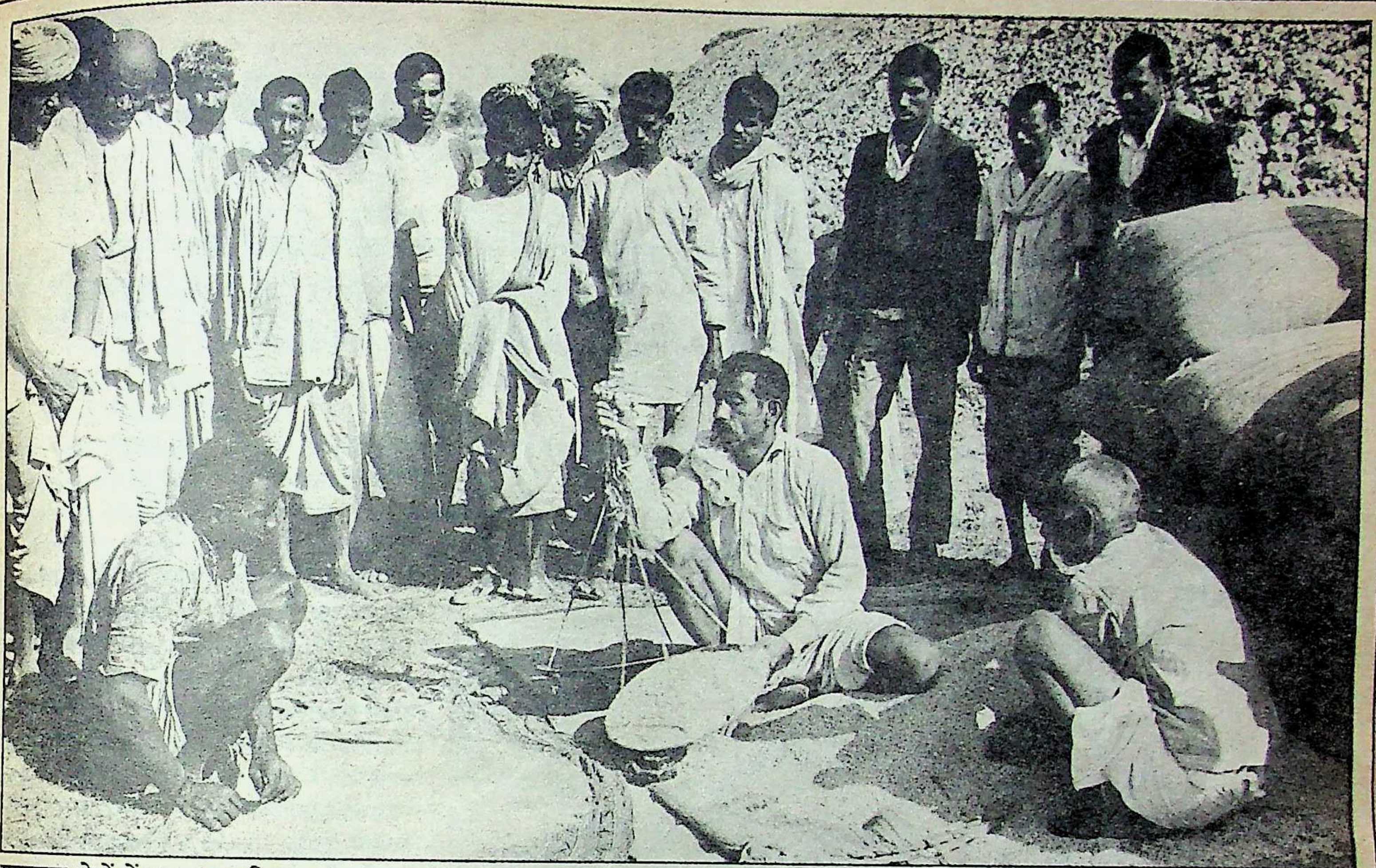

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का वितरण

कीटनाशक रसायनों पर ५० प्रतिशत तथा कुरमुला कीट के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त रसायनों पर ७५ प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

कृषि की विकसित नवीनतम तकनीक को कृषकों तक पहुंचाने तथा उसे कृषकों के खेतो पर लागू कराने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रशिक्षण एवं संपर्क योजना आरम्भ की गयी है। वर्ष १९८५-८६ में इस योजना का सूत्रपात हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा वाराणसी में इसे लागू किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना को पांच अन्य जनपदों—मिर्जापुर, गोंडा, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी में लागू किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि प्रसार के लिए किसान सहायकों की नियुक्ति की गयी है। १२०० किसान परिवारों पर एक किसान सहायक की नियुक्ति की गयी है, जो सम्पर्क कृषकों से प्रत्येक पक्ष में निर्धारित तिथि को कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराते हैं।

प्रदेश में भूमि कटाव, बीहड़, जलभराव तथा ऊसर भूमि की समस्याएं बड़े पैमाने पर विद्यमान हैं। वर्ष १९८३-८४ की भू-उपयोगिता आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग १२०.०२ लाख हे० भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें ३६ ७४ लाख हे० कृषि अंतर्गत भूमि, १२.३ लाख हे० बीहड़ भूमि, ११.०५ लाख हे० ऊसर भूमि, १०.७ लाख हे० बाढ़ तथा जलभरावग्रस्त भूमि तथा ४१.२३ लाख हे० भूमि अन्य समस्याओं से ग्रसित है एवं समस्याओं के निदान हेतु प्रदेश में व्यापक स्तर पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में कटावग्रस्त तथा बीहड़ भूमि के उपचार हेतु चलाये जा रहे भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष १९८७-८८ में १.०९ लाख हेक्टयर कटाव ग्रस्त भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है।

शुष्क कृषि हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष १९८७-८८ में झांसी, हमीरपुर तथा बांदा जनपदों में ८ भूमि संरक्षण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार बीहड़ भूमि की समस्या के तीव्र विकास हेतु योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से चम्बल तथा यमुना नदियों के जलागम क्षेत्र में बीहड़ भूमि के उपचार हेतु एक बृहत कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष १९८७-८८ में ७.४४ करोड़ की लागत से २०.५० हेक्टेयर बीहड़ भूमि के सुधार का कार्यक्रम आगरा एवं इटावा जनपदों में चलाये जाने की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है। इसके लिए ५ इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं तथा ४ अन्य भूमि संरक्षण इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

प्रदेश में ऊसर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा सुधारकों को प्रयोग हेतु कृषकों को अनुदानित दर पर वितरण किया जा रहा है। तीन हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को ७५ प्रतिशत अनुदान तथा अन्य कृषकों को ५० प्रतिशत अनुदान मृदा सुधारकों के मूल्य पर देय है। वर्ष १९८७-८८ में २५,००० हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केंद्र पुरोनिर्धारित ऊसर समंवित योजना के अंतर्गत १२२६० हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार भी सम्मिलित है।

इस वर्ष १९८७-८८ में खरीफ में प्रदेश के ५५ जनपद अवर्षण तथा सूखे से व्यापक रूप से प्रभावित हुए। इसके फलस्वरूप खरीफ की फसलों को अत्यधिक क्षति हुई। खरीफ के लिए इस वर्ष खाद्यान्न का ११६.७० लाख मे० टन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि गत वर्ष खरीफ में १०४.६७ लाख मे० टन का उत्पादन हुआ था। खरीफ की फसलों के लिए लगभग १.६१ लाख कुंतल गुणात्मक बीज तथा ५.४२ लाख मे० टन उर्वरकों का वितरण किया गया है।

शासन किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सचेत है तथा उनके निराकरण हेतु हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। हरित क्रांति को सफल बनाने में सरकार के साथ किसानों की बराबर की भागीदारी है।

ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट

राजस्थान सरकार के लिए सिरदर्द

फेयरफैक्स के मामले पर ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्थान इंका के छात्र संगठन एनएसयूआई के पूर्व महासचिव मणीभद्र बगड़ा ने वीपी सिंह, अरुण शौरी तथा अन्य लोगों के खिलाफ न्यायिक मैजिस्ट्रेट जयपुर की अदालत में शिकायत दायर कर दी। लेकिन फंस गयी आयोग की रिपोर्ट ही। ऐसा कैसे हो गया?

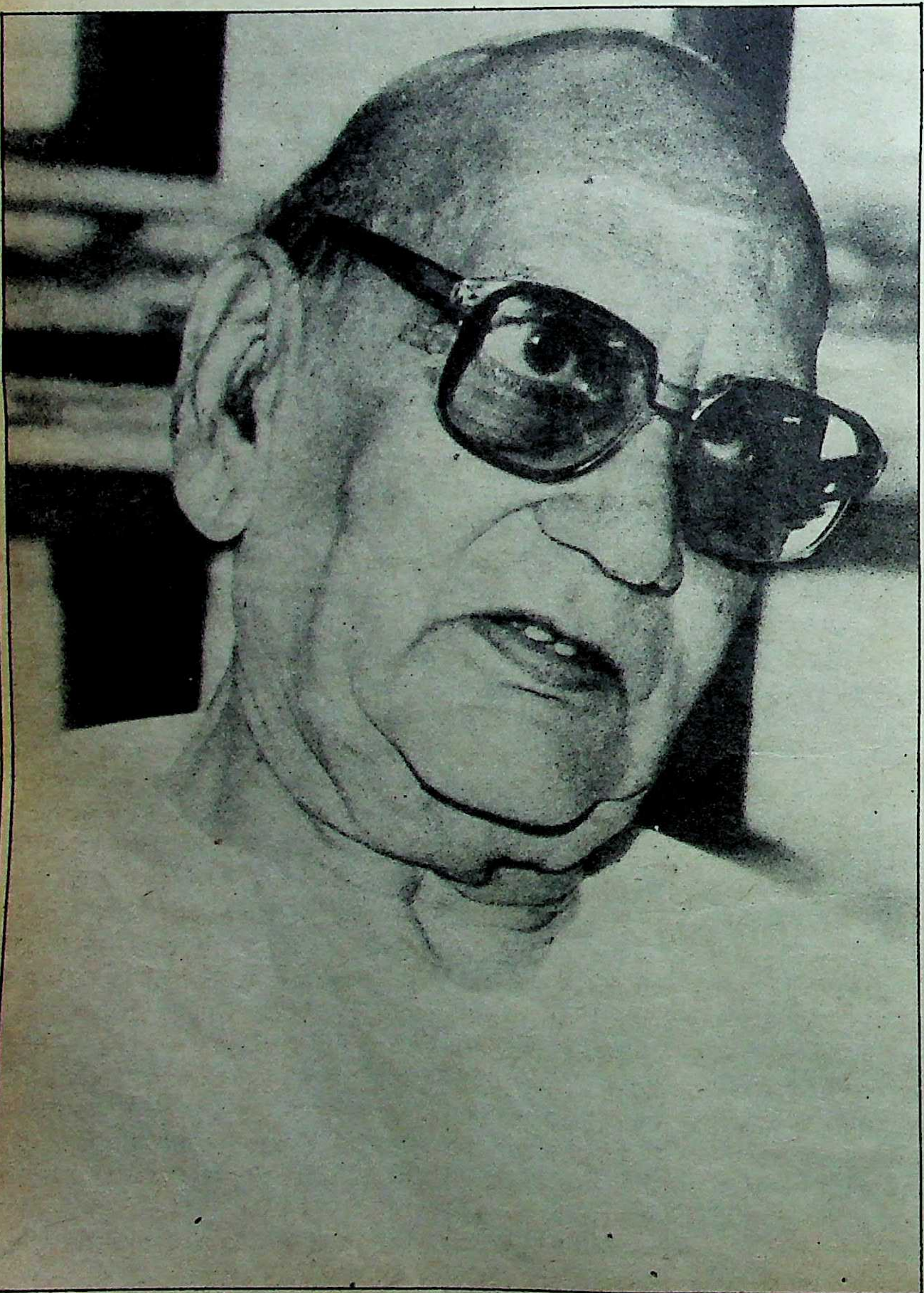

अब मैं मुक्त हूं: राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता नाथू लाल जैन

कतिपय भारतीय कंपनियों के कथित आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी फेयर फैक्स को सौपे जाने के औचित्य की समीक्षा करनेवाली ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान सरकार के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गयी है जिसका फिलहाल कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वनाथप्रताप सिंह, बांबे डाइंग कंपनी के अध्यक्ष नसली वाडिया, 'इंडियन एक्सप्रेस' के मालिक रामनाथ गोयनका, संपादक अरुण शौरी, वित्त सलाहकार गुरुमूर्ति और भारत सरकार के अधिकारी भूरेलाल एवं विनोद पांडेय के खिलाफ जयपुर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) की अदालत में दायर एक याचिका अब राज्य के उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। किंतु न्यायिक प्रक्रिया की पेंचीदगी और राज्य सरकार, राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और सीबीआई की राज्य शाखा की संदेहास्पद भूमिका के कारण सरकार का पक्ष हास्यास्पद बन गया है और ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट के निरर्थक हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। फेयर फैक्स के मामले पर गठित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसपी ठक्कर और एस नटराजन के आयोग ने अपनी रिपोर्ट १० दिसंबर १९८७ को भारत सरकार को सौंप दी थी। १४ दिसंबर '८७ को राजस्थान कांग्रेस-इ के छात्र संगठन एनएसयूआई के पूर्व महासचिव मणीभद्र, बगड़ा ने जयपुर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) की अदालत में आपराधिक दंड विधान की धारा १९० के अंतर्गत एक शिकायत दायर की। इसमें कहा गया था कि ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह (बगड़ा) इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विश्वनाथप्रताप सिंह ने संविधान के अनुच्छेद ७५ (४) के अंतर्गत ली गयी शपथ को झुठलाते हुए दंडनीय अपराध किया है। शिकायत में विश्वनाथप्रताप सिंह तथा अन्य ऊपरोक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की व्यवस्थाओं के तहत सजा पाने योग्य बताते हुए बगड़ा ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के दो अधिकारियों, भूरेलाल और विनोद पांडेय ने सारी

साजिश वीपी सिंह के साथ राजस्थान के देवगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा जयपुर के प्रतिष्ठित होटलों में बैठ कर की। लिहाजा इस प्रकरण की जांच करवाना इस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है। शिकायत पेश करते हुए बगड़ा के वकील महेशचंद्र शर्मा दोसावला ने इन व्यक्तियों को भादंसं की धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४०६, ४०९ और १२०-'बी' (यानी सरकारी गोपनीयता कानून, 'फेरा' अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, सीमा शुल्क अधिनियम और आयात-निर्यात अधिनियम) के तहत अपराधी बताते हुए अदालत से पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश देने का अनुरोध किया। महेशचंद्र की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ओमप्रकाश शर्मा नें उसी दिन दंड प्रक्रिया की धारा १५६ (३), १५५ (२.) तथा अन्य व्यवस्थाओं के तहत पुलिस अधीक्षक (सीबीआई) को इस प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिये।

लोगों में हंसी की चीज बनी बगड़ा की शिकायत तब महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी जब २७ दिसंबर को उपरोक्त अभियुक्तों में से अरुण शौरी और गुरुमूर्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट में दंड प्रक्रिया की धारा ४८२ के अंतर्गत अपनी याचिका प्रस्तुत कर न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दे दी। वह रविवार का दिन था और हाईकोर्ट में शरतकालीन अवकाश चल रहा था, फिर भी कार्यवाहक न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा ने उक्त प्रतिवाद यायिका की सुनवाई का निर्णय लिया। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपराह्न १.०० बजे बगड़ा के वकील दोसावाला को टेलीफोन से सूचित किया कि याचिका के सिलसिले में उन्हें न्यायमूर्ति लोढ़ा की अदालत में उपस्थित होना है। २.०० बजे सुनवाई शुरू हुई। अरुण शौरी अदालत की अगली कतार में बैठे थे। दोसावाला ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि अपराधी की हैसियत से अदालत में आये आदमी को इस तरह बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर न्यायाधीश लोढ़ा ने शौरी को खड़े रहने के लिए कहा। याचिका के जवाब में जब दोसावाला बोलने लगे तो शौरी उन्हें बार-बार टोंकने लगे, जिससे न्यायाधीश को उन्हें चुप रहने के लिए कहना पड़ा। शौरी और पांडेय के वकील अरुण जेटली ने जहां अदालत से न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया वहीं दोसावाला ने इस आदेश को ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित बताते हुए जेटली की दलील का विरोध किया। सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश पर सीबीआई ने जांच का काम शुरू किया या नहीं, यह दोनों पक्षों में से किसी को भी मालूम नहीं था। न्यायाधीश लोढ़ा ने मैजिस्ट्रेट के आदेश के संबंध में अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को अदालत में हाजिर होने तथा मामले से संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की फाइल मंगवाने के आदेश जारी किये और याचिका पर बहस के लिए ४ जनवरी '८८ की तारीख तय कर दी।

वीपी दंडित हों: मणीभद्र बगड़ा

इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रुख से राज्य सरकार चौंक गयी। दरअसल ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट ने कुछं ऐसे मुद्दे पेश किये हैं, जिनसे कोई भी नागरिक अदालत के जरिये सरकार को मामले से संबद्ध जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकता है। जांच आयोग अधिनियम १९५२ के तहत ठक्कर-नटराजन आयोग अपनी रिपोर्ट में संबंधित मामलों पर जांच की सिफारिश भी कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इस स्थिति ने जहां शौरी और गुरुमूर्ति को मैजिस्ट्रेट के आदेश रोकने के लिए हाईकोर्ट में प्रतिवाद याचिका पेश करने को मजबूर कर दिया, वहीं राज्य सरकार के तत्कालीन महाधिवक्ता नाथूलाल जैन और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की नींद हराम कर दी। कानून की इस पेंचीदगी से जब जैन ने जोशी को जबानी तौर पर अवगत कराया तब जोशी ने उन्हें इस दिशा में चौकस और सक्रिंय रहने के लिए सावधान किया। जैन उन दिनों दिल की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने इस जबानी बातचीत को औपचारिक बनाते हुए १६ जनवरी '८८ को मुख्यमंत्री जोशी को एक पत्र भी लिखा।

बहरहाल, ४ जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर सीबीआई के वकील ने बताया कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किंतु पूरे प्रकरण पर सीबीआई मुख्यालय बारीकी से विचार कर रहा है, लिहाजा वस्तुस्थिति से अदालत को वाकिफ कराने के लिए तीन हफ्ते का समय मिलना चाहिए। इस पर अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई २ फरवरी के लिए आगे बढ़ा दी। ४ जनवरी की सुनवाई से केंद्र सरकार के भी कान खड़े हो गये। कहां तो दिल्ली में वह ठक्कर-नटराजन आयोग पर विचार के लिए चार केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति नियुक्त कर रखी थी, और कहां जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट इसी रिपोर्ट पर आधारित शिकायत के विरुद्ध अभियुक्तों की याचिका पर विचार कर रहा था। दिल्ली की निगाह में अपने को चौकस दिखाने के लिए ही मुख्यमंत्री जोशी ने महाधिवक्ता जैन से १६ जनवरी को वह पत्र प्राप्त किया था जिसमें उन्हें इस प्रकरण से देर से अवगत कराने के लिए खेद प्रकट किया गया था। जानकार सूत्रों के अनुसार, इसके पहले केंद्र सरकार इस मामले की जानकारी न होने के लिए जोशी को आड़े हाथों ले चुकी थी।

विधि सचिव के लिखित आदेश पर महाधिवक्ता जैन २ फरवरी '८८ को न्यायाधीश लोढ़ा की अदालत में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित हुए। फौजदारी के मामलों में राज्य सरकार स्वभावतः एक पक्ष होती है। लेकिन इस वाद में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए महाधिवक्ता एक पक्ष बने। उस दिन सीबीआई के वकील एसपी त्यागी ने आश्चर्यजनक ढंग से अपने मुख्यालय के निर्देशों का हवाला देते हुए अदालत को बताया, "न्यायिक मैजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर, सीबीआई को सीधे निर्देश देने में सक्षम नहीं है, उनके निर्देश केवल राज्य सरकार के आग्रह पर स्वीकार कियें जा सकते हैं।"

सीबीआई की यह दलील कल्पना से बाहर की चीज थी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले (जो संपत लाल तथा अन्य के जर्नल 'सुप्रीम कोर्ट क्राइम्स', वाल्यूम एक, ८६-९१ में वर्णित हैं) इस बात को स्थापित करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा १५६ (३) के तहत कोई भी न्यायिक मैजिस्ट्रेट इस तरह के मामलों में जांच के आदेश दे सकता है। फिर, मैजिस्ट्रेट ने अपने १४ दिसंबर के आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि सीबीआई को ये आदेश लागू करने में कोई तकनीकी अड़चन सामने आये तो वह स्पष्टीकरण के लिए इस न्यायालय में उपस्थित हो सकती है। गौर-तलब बात यह भी है कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर का न्यायालय आर्थिक अपराधों की न्यायिक समीक्षा करने वाला राज्य का एकमात्र न्यायालय है। इसमें ज्यादातर सीबीआई द्वारा जांचे-परखे वाद ही आते हैं। हाईकोर्ट में सीबीआई के ऐसे बयान के बाद विचाराधीन मामले की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान कोई भी कर सकता है।

त्यागी के बयान के बाद शौरी और गुरुमूर्ति के वकील जेटली ने कहा कि इस मामले को और आगे खींचना अब बेतुका है। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता जैन द्वारा वाद के अध्ययन के लिए समय मांगे जाने पर न्यायाधीश लोढ़ा ने अगली सुनवाई के लिए २४ फरवरी '८८ की तिथि तय कर दी। इसके बाद ही वकीलों की हड़ताल शुरू हो गयी, इसलिए इस रोचक मुकदमे में केवल तारीखे मिलती रहीं। इसी बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा असम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होकर गोहाटी चले गये और १५ दिन बाद सेवानिवृत्त हो गये। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दवे की अदालत में जारी रही जहां मामले की अगली सुनवाई १२

ऊह... आह... आउच को दूर भगाइए !

बदन दर्द और पीठ दर्द पर भी उसी तरह ध्यान देने की ज़रूरत है जैसे कि मोच, पेशियों में खिंचाव और जोड़ों की जकड़न पर.

इसलिए आयोडेक्स हमेशा अपने पास रखिए.

आयोडेक्स न सिर्फ़ दर्द से छुटकारा दिलाता है बल्कि चोट खायी कोशिकाओं को भी अच्छा करता है.

और आयोडेक्स दिन में दो बार मलें तो दुगुना फ़ायदा मिले.

इसलिए 'ऊह', 'आह' और 'आउच' को दूर भगाने के लिए आयोडेक्स लगाइए, और काम पर जाइए.

HTA 1711

आयोडेक्स®
मलिए,
काम पर चलिए.

SKF — एस के एफ का उत्पादन.

जुलाई '८८ को होने वाली है। इधर राज्य का नेतृत्व बदल गया। नये मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के सामने महाधिवक्ता नाथूलाल जैन ने अस्वस्थता के कारण पद छोड़ने का अपना निश्चय रखा। माथुर ने सरकार को पक्ष बनाने की सलाह दी। विधि सचिव ने भी उन्हें इसी आशय का लिखित आदेश दिया। इस सलाह और आदेश के बावजूद जैन ने गत ३० मई को महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह इंका के पूर्व सांसद और प्रमुख अधिवक्ता दिनेश स्वामी को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसपी ठक्कर और न्यायमूर्ति एस नटराजन ने जिन तथ्यों के आधार पर अपनी जांच में नामज़द लोगों को दोषी पाया, उन्हें कोई न्यायालय किस आधार पर निर्दोष घोषित कर सकता है? यह प्रश्न जब 'माया' ने पूर्व महाविधवक्ता जैन के सामने रखा तब उनका कहना था, "मैंने इस तथ्य और इसकी गंभीरता को समझा था और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी थी।" जैन का मानना है कि इस गंभीर मामले में सीबीआई का रोल आश्चर्यजनक रहा है। उधर केंद्र सरकार सारे प्रकरण में राज्य सरकार की भूमिका से खफा रही है। साथ ही जैन और न्यायाधीश (अब अवकाश प्राप्त) लोढ़ा भी संदेहों की लपेट में आ गये हैं। खबर थी कि श्री लोढ़ा कांग्रेस-इ के टिकट पर पाली संसदीय सीट का उपचुनाव लड़ने का मन बनाये हुए थे। केंद्रीय विधि राज्यमंत्री एचआर भारद्वाज भी इसी पक्ष में थे। कहते हैं, इसी बीच किसी ने राजस्थान से पत्र भेजकर प्रधानमंत्री सचिवालय को अरुण शौरी में श्री लोढ़ा की दिलचस्पी का जिक्र कर दिया। नतीजतन श्री लोढ़ा को इंका की ओर से निराश होकर पाली उपचुनाव के लिए अपने पुराने जनसंघी मित्रों के साथ भाजपा में शामिल होना पड़ा। इस पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर जैन ने 'माया' को बताया, "सरकार क्षेत्र में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि तथाकथित पत्र मेरे द्वारा ही प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, जो कि सच नहीं है। खैर, इस चर्चा के साथ ही राज्य सरकार को अचानक मेरी अस्वस्थता का ख्याल आया, और सरकार ने नया महाधिवक्ता तलाश लिया।" बहरहाल, चर्चित वाद कानून की जिस जटिलता में फंस गया है वहां सरकारी पक्ष अपने को असहाय-सा अनुभव करने लगा है। सवाल उठता है, ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित इस वाद में दर्ज अभियुक्तों को यदि राजस्थान हाईकोर्ट बेदाग करार दे देता है (जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही है) तो आयोग की रिपोर्ट का क्या हश्र होगा? फिर केंद्र और राज्य सरकार की स्थिति क्या होगी?

—ओम सैनी

यह प्रश्न जब 'माया' ने पूर्व महाविधिवक्ता जैन के सामने रखा तब उनका कहना था, "मैंने इस तथ्य और इसकी गंभीरता को समझा था और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी थी।"

जांच लाजिमी है: दोसावाला

साक्षात्कार/**मोतीलाल वोरा**

पार्टी को सत्ता के दलालों से मुक्त कराना है

केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं नागरिक उड्डयन मंत्री मोतीलाल वोरा पत्रकारिता की दुनिया से राजनीति के बीहड़ में आनेवाले राजनेता हैं। दो दशकों के असमाप्त राजनीतिक जीवन में वोरा के साथ नाटकीय उपलब्धियां जुड़ी रही हैं। मध्यप्रदेश में राज्यमंत्री रहने के बाद संगठन के मुखिया पद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकस्मिक छलांग, नाटकीय व उनके खेमे के लिए अप्रत्याशित विदाई और फिर केंद्र में काबीना मंत्री का पद—इस अहसास की पुष्टि करते हैं कि उनके जीवन में कभी भी कुछ भी घट सकता है।

इन दिनों वोरा सुर्खियों में इसलिए हैं, क्योंकि उन्होंने सिंधिया के साथ मध्यप्रदेश के दौरे कर अर्जुनसिंह की नींद हराम कर रखी है। इस अभियान का एक नतीजा यह भी निकला है कि टकराव से परहेज रखने वाले वोरा सर्वथा नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत है, वोरा से 'माया' की बातचीत का सार-संक्षेप:

माया: *आपके नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद आपसे मध्यप्रदेश को जो अपेक्षाएं थीं, वे कहां तक पूरी हुई हैं?*

वोरा: आपने मध्यप्रदेश की बात की तो शुरुआत मध्यप्रदेश से ही करते हैं। मेरे काल में सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ है कि भोपाल को 'बेस-स्टेशन' बनाकर बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, जबलपुर, खजुराहो, सतना, रीवां, गुना और ग्वालियर के लिए विमान सेवा शुरू की गई है।

माया: *बढ़ती हुई मांग, देश के विशाल क्षेत्रफल तथा भौगोलिक संदर्भों को देखते हुए क्या पर्याप्त हवाई बेड़ा व अड्डे हैं?*

वोरा: जरूरतों के लिहाज से हवाई बेड़ा कतई पर्याप्त नहीं है। इस समय देश में ८५ हवाई अड्डे हैं। मैंने नागर विमान मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नये हवाई अड्डों के निर्माण, रन-वे के विस्तार एवं अड्डों को बेहतर बनाने के काम में तेजी लाने की कोशिश की है। लक्षद्वीप में अगाथी में एयर पोर्ट बनाया गया है और मद्रास से अगाथी उड़ान प्रारंभ हो गई है। कालीकट और दिमापुर में अड्डे बन कर चालू हो गए हैं। जल्द ही सालेम और तूतीकोरिन में भी अड्डे बनाए जाएंगे। कलकत्ता से पटना और गया के अलावा पूर्वोत्तर में अगरतल्ला के लिए विमान सेवा प्रारंभ की गई है। इंदौर में विमानों के रात्रि-अवतरण की व्यवस्था की गई है। खजुराहो में काम चालू है। रायपुर और जबलपुर में भी इंतजाम किया जा रहा है। जयपुर और रायपुर के दौरे में मैंने पाया कि वहां सुधार की काफी गुंजाइश है।

माया: *घरेलू व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उड्डयन संबंधी क्या कोई विशेष योजना है?*

वोरा: मैंने छोटे-छोटे नगरों, विशेषकर पर्वतीय, दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों से संपर्क के लिए छोटे विमानों की सेवा उपलब्ध कराने के समयबद्ध (निश्चित समयावधि के) कार्यक्रम बनवाए हैं। आगामी पांच सालों में बड़े पैमाने पर विस्तार होगा। कई योजनाएं हैं। जल्द ही इसी गर्मी में पांच बोइंग ७३७ विमान हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगे। सार्क देशों को दिल्ली से जोड़ने की हमारी योजना है। हम दिल्ली को ढाका से जोड़ चुके है। अब दिल्ली को काठमांडू, मालद्वीप, कोलंबो, इस्लामाबाद, कराची से जोड़ा जाएगा। ताशकंद-काबुल-दिल्ली-काठमांडू सेवा प्रारंभ करने का भी विचार है। चार्टर्ड विमानों के लिए हमारे पास अभी सिर्फ चार अंतरराष्ट्रीय विमान तल हैं। हैदराबाद, अहमदाबाद और तिरुअनंतपुरम को अंतरराष्ट्रीय विमानतलों में बदलने की मांग पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में कलकत्ता व बंबई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की १९५ करोड़ रुपयों की योजना है। एयर इंडिया में अगले वर्ष दो बड़े विमान आने वाले हैं। ७४७-३०० काबी नामक इन एयर बस कार्गो की लागत ३७१ करोड़ ७४ लाख रुपये है।

माया: *वायुदूत सेवा को लेकर उड़ान के बीच दरवाजा खुलने तक के बारे में अनेक तरह की शिकायतें हैं। क्या यह सेवा संतोषप्रद है?*

वोरा: आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वैसी सिर्फ एक घटना हुई है। बाकी वायुदूत सेवा संतोषप्रद है। वायुदूत में हमारे पास कुल १९ विमान हैं, जिनमें १० डार्नियर और ९ फोकर एवं एवरो हैं। पहले वायुदूत सेवा में विमान परिचारिकाएं नहीं होती थीं। अब सभी में एयर-होस्टेस रखी गई हैं। फिलहाल ९५ स्थानों के लिए वायुदूत सेवा उपलब्ध है और आप अचरज करेंगे कि अन्य ४० स्थानों के लिए मांगें लंबित हैं। ये मांगें हम सातवीं योजना के अंत तक पूरी कर सकेंगे, बशर्ते राज्य सरकारें सहयोग करें।

माया: *आम शिकायत है कि देश में जीवन रक्षक आवश्यक दवायें बहुधा उपलब्ध नहीं होती हैं?*

वोरा: ऐसी शिकायतें मेरी जानकारी में आई हैं। हम इन औषधियों की आपूर्ति व वितरण-प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के प्रयास कर रहे हैं।

माया: *एक खटकनेवाली बात यह है कि सरकार एलोपैथी को ही प्रोत्साहन दे रही है और आयुर्वेद होम्योपैथी व यूनानी आदि पद्धतियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है...?*

वोरा: सरकार का ध्यान देशी पद्धतियों की ओर भी है। आयुर्वेद, यूनानी व सिद्ध आदि पद्धतियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।

माया: *आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों का विशेष महत्व है। ऐसे में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण से क्या अमूल्य जड़ी बूटियों का विनाश नहीं होगा?*

वोरा: वन संरक्षण अधिनियम ८० के तहत अब वनों की कटाई के लिये केंद्र की मंजूरी जरूरी है। इससे वनों की कटाई पर अंकुश लगा है। सरकार निर्वनीकरण रोकने के लिए सघन प्रयास कर रही है।

माया: *आप इन दिनों मध्यप्रदेश के काफी दौरे कर रहे हैं। क्या यह एक नई परिपाटी नहीं है?*

वोरा: मेरी नजरों में दौरे नई परिपाटी कतई नहीं हैं। हम लोग पार्टी कार्यक्रम को, प्रधानमंत्री के संदेश और नीतियों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के प्रयोजन से दौरे कर रहे हैं। इनका मकसद पार्टी में मजबूती लाना है।

माया: *आप ये दौरे स्वेच्छा (अपनी पहल) से कर रहे हैं या इनके लिये आलाकमान ने आपसे कहा है?*

वोरा: हम लोग ये दौरे अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी के निर्देश पर कर रहे हैं।

माया: *लेकिन अर्थ तो यह लगाया जा रहा है कि आप अपने समर्थकों को गोलबंद करने और अर्जुनसिंह को परेशानी में डालने के लिये सिंधिया के साथ ये दौरे कर रहे हैं...?*

वोरा: लोग अपने तरीके से व्याख्या करने को स्वतंत्र हैं। किंतु हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। हमने तो मुख्यमंत्री से भी कहा है कि वह हमारे साथ चलें। मैंने तो गुटबंदी को बढ़ावा देने की राजनीति कभी नहीं की। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे कांग्रेस को क्षति पहुंचे।

***माया:* तो क्या यह कयास गलत है कि आप अर्जुनसिंह को कमजोर और अंततोगत्वा उन्हें अपदस्थ करने की मुहिम में लगे हैं?**

वोरा: अर्जुनसिंह को दिल्ली से भोपाल प्रधानमंत्री ने भेजा है, लिहाजा उन्हें कमजोर करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री ने कहा और काफी जोर देकर कहा है कि कांग्रेस को सत्ता के दलालों से मुक्त करना है। उनके इस अभियान में हम सब शरीक हैं।

***माया:* तो क्या आपको लगता है कि मध्यप्रदेश में भी सत्ता के दलाल हैं?**

वोरा: मैं मानता हूं कि मध्यप्रदेश में भी सत्ता के दलाल हैं। सत्ता के दलाल हर कहीं हैं। हमें उनसे सतर्क रहना है। सत्ता के दलाल वे हैं जो पार्टी के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की राजनीति खेल रहे हैं।

***माया:* क्या कारण है कि इन दिनों आप सारे दौरे सिंधिया के ही साथ कर रहे हैं?**

वोरा: यह कोई नई बात नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी सिंधिया के साथ कई दौरे किये हैं।

***माया:* पिछले दिनों सांसद कमलनाथ ने भी आपके साथ दौरे करने का इरादा व्यक्त किया है... ?**

वोरा: कमलनाथ का स्वागत है। वह आएं, साथ चलें। मैंने तो मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह से भी कहा है कि वह हमारे साथ चलें, दौरे करें, ताकि कानाफूसी की राजनीति बंद हो।

***माया:* क्या इस बारे में आपकी अर्जुनसिंह से बातचीत हुई है?**

वोरा: उन्होंने सतना-रीवा के दौरे में साथ आने की बात कही थी, लेकिन वह किसी कारणवश—संभवतः व्यस्तता कें चलते—आ नहीं सके। उन्होंने अपनी जगह राजमणि पटेल को भेज दिया। मैंने अर्जुनसिंह से मिलने में कभी गुरेज-परहेज नहीं किया। जब भी वह आए, मैं उनसे मिला। जब मैं मुख्यमंत्री था तब, जब भी वह भोपाल आए, मैंने उनकी अगवानी की।

***माया:* कहा जा रहा है कि आप व सिंधिया के और जवाब में अर्जुनसिंह के दौरे निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं तक को गुटों में बांट रहे हैं... !**

वोरा: पार्टी का कार्यकर्ता किसी धड़े या गुट से बंधा हुआ नहीं है। वह सिर्फ पार्टी की नीतियों व प्रधानमंत्रीजी के प्रति समर्पित है।

***माया:* आपकी सरकार में मंत्री रहे रसूल अहमद सिद्दकी का आरोप है कि आपके जाने के बाद गैस-पीड़ितों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ऐसी बातें आपकी जानकारी में आई हैं?**

वोरा: अभी तक तो नहीं। लेकिन अबकी भोपाल जाने पर मैं गैस-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। और यह मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं ऐसा करूं। गैस-पीड़ितों के हितों की अगर उपेक्षा होती है, तो यह दुर्भाग्य होगा।

***माया:* मध्यप्रदेश में जनमोर्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है?**

वोरा: मध्यप्रदेश में जनमोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका बस कागजी अस्तित्व है।

छाया: रवि विलियम —सुधीर सक्सेना

थानेदार अपने ही आतंक का शिकार

ऐसे जुल्म तो नवाबी दौर में भी नहीं देखे: प्रताप सिंह, लाल सिंह और कालू राम

अपने गिरेबां में झांकने की न तो पुलिस की आदत है, और न ही मानवीयता से कोई सरोकार। कम-से-कम राजधानी के समीप रायसेन जिले के सुल्तानपुर गांव में हुए घटनाक्रम से तो यही लगता है। सुल्तानपुर में बुधनी जैसी घटना नये सिरे से दोहरायी गयी है। बुधनी की ही भांति सुल्तानपुर में भी पुलिस ने एक गुमशुदा व्यक्ति को मृत मानकर यातना और प्रताड़ना के अपने 'बेनुक्स नुस्खों' से ग्रामीणों से यह कुबूल करवा लिया कि उन्होंने लापता व्यक्ति की हत्या की है।

घटनाक्रम: सुल्तानपुर थाने के थानेदार हनुमंतसिंह राजपूत और थाने के सिपाहियों की बर्बरता के शिकार ५ व्यक्तियों के नाम हैं: आशाराम, कालूराम, नरेंद्र, प्रताप और लाल सिंह। 'माया' संवाददाता की इनमें से ४ व्यक्तियों से बातचीत हुई। पांचवें व सबसे महत्वपूर्ण आशाराम से मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि चार-पांच दिन बाद तक उसका कोई अता-पता नहीं था। आशाराम वही व्यक्ति है जिसने प्रताड़ना से बचने के लिए यह स्वीकार कर लिया था कि उसने ग्राम कोहनिया निवासी मुन्ना चमार की हत्या की है। यहां यह बता देना प्रासंगिक होगा कि आशाराम मुन्ना का साला है और उसकी बहन भूरीबाई (आयु २० वर्ष) मुन्ना लाल को ब्याही है।

कालूराम, नरेंद्र, लालसिंह और प्रतापसिंह के अनुसार उन्हें बुधवार, २५ मार्च को रात में लगभग साढ़े बारह-एक बजे पुलिस ने सोते से जगाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें व आशाराम को मुश्कें कसकर जीप में पटक दिया और सुल्तानपुर थाने ले गयी। थानेदार की एक ही रट थी कि तुम लोगों ने मुन्ना का 'मर्डर' किया है। मेहनत-मजदूरी से गुजर-बसर करने वाले बूढ़े लालसिंह और आदिवासी प्रतापसिंह समूचे प्रकरण को अपनी बदनसीबी मानते हैं और कहते हैं— "हम लोगों ने पहले कभी थाने का मुंह नहीं देखा था। पहली दफा पुलिस के चक्कर में आए। बेवजह पुलिस की मार खानी पड़ी।" तीनों के मुताबिक आशाराम को थानेदार ने लात-घूंसों व डंडे से इस कदर पीटा कि आशाराम का चलना-फिरना मुहाल हो गया था। नरेंद्र बताता है कि उसकी नाक से पिटाई के कारण, खून निकलने लगा था।

इन चारों लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस ने उन लोगों के साथ-साथ फरियादी की भी खूब गत बनाई। पुलिस ने मुन्ना की जवान पत्नी को थाने बुला लिया और प्रताड़ित किया। उसे छह रोज थाने में बंद रखा गया।

बहरहाल, पुलिस ने अपने तरीकों से आशाराम से यह कुबूल करवा लिया कि उसने अपने बहनोई मुन्ना का कतल किया है। यही नहीं, पुलिस ने उसे समीपवर्ती गांव खीवी ले जाकर कब्र भी खुदवाई, जहां से एक बच्चे का कंकाल निकला। गांव में कब्र की खुदाई चल ही रही थी कि सिपाही जगमोहन ने वहां पहुंचकर थानेदार को मुन्ना के जीवित होने की खबर दी। सुनकर थानेदार के हाथों के तोते उड़ गये। इसके बाद उसने न केवल सबको मुंह बंद रखने की हिदायत देकर छोड़ दिया बल्कि बताते हैं, उसने आशाराम को अपने हाथों से नहलाया-धुलाया और खिलाया-पिलाया भी। एक आशंका यह भी है कि आशाराम अभी भी कहीं-न-कहीं पुलिस के कब्जे में है। कारण यह है कि अपने बचाव के लिए वह पुलिस के हाथों में तुरुप का पत्ता है। उससे मनचाहा बयान दिलवा कर थानेदार बाइज्जत बरी हो सकता है।

कार्रवाई: इस प्रकरण में संतोष की बात यही

है कि उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। पुलिस महानिरीक्षक एनएन विरमानी ने उप पुलिस निरीक्षक आरआर नेगी को चौबीस घंटों में रपट देने को कहा। प्राथमिक जांच में जब आरोप सही निकले तो थानेदार को निलंबित कर दिया गया और आगे की जांच का काम पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया गया।

ताजा खबर है कि पुलिस अब सारे मामले को मनगढ़ंत निरुपित करने पर तुली हुई है। सूत्रों का कहना है कि थाने में हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं है। परंतु प्रताड़ित चारों व्यक्तियों का कहना है कि मामला गुमशुदगी का दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस ने हत्या के मामले के तौर पर लिया। मामले को नया मोड़ देने वाले दो हलफनामे भी इस बीच हाथ लगे। मुन्ना और भूरीबाई ने एक ही दिन (२ जून को) रायसेन में अलग-अलग हलफनामा देकर कहा कि पुलिस ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की। दोनो ने अपने बयान में कहा कि मुन्ना ने पालीवाल नामक व्यक्ति को मायके में भूरी के साथ जबरन कुकृत्य करते हुए देख लिया था। पति के डांटने-फटकारने पर पालीवाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी और आशाराम के साथ पालीवाल कुल्हाड़ी लेकर मुन्ना के पीछे चला गया था। मुन्ना ने अपने बयान में पत्नी के साथ कुकर्म होने की पुष्टि की ओर कहा कि वह भयभीत होकर भाग निकला था और भटक कर बाड़ी पहुच गया। जेब में पैसे न होने से वह घर न पहुंच सका तो पिता ने थाने में रपट दर्ज करा दी। वैसे, भूरी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि जांच के दौरान उसने कहा था कि उसके पति को आशाराम व पालीवाल ने मार डाला होगा।

आशाराम कहां है ? : इस सारे प्रकरण में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भूरी के किसी से अवैध संबंध थे या नहीं। यह भी बहुत अहमियत नहीं रखता कि मुन्ना नामक व्यक्ति गायब हुआ और फिर लौट आया। अहमियत इस बात की है कि पुलिस ने ५ बेगुनाहों को पकडा, ३ दिन अकारण हिरासत में रखा और सबसे बड़ी बात यह है कि डंडे के जोर पर यह कुबूल करवा लिया कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की है, हालांकि वह आदमी जीवित था। बुधनी और सुल्तानपुर राजधानी से ज्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए उनकी गुहार किसी-न-किसी तरह राजधानी के कानों तक पहुंच जाती है। मगर हो सकता है कि ऐसी घटनाएं दूर दंराज के इलाकों में भी घटती हों जहां के आदमी में भोपाल पहुंचने की हिम्मत और सामर्थ्य नहीं हो। सुल्तानपुर कांड की जांच में मुद्दे क्या हैं, पता नहीं चल सका। परंतु जांच में यह पता लगाना जरूरी है कि आशाराम कहां है और मुन्ना व भूरी ने बयान स्वेच्छा से दिये हैं या किसी दबाव में ? सर्वहारा की चिंता का ऐलान करने वाली सरकार के लिए जांच की घिसी-पिटी लीक पीटने से ज्यादा जरूरी यह होगा कि वह पुलिस की चंगेजी-मनोवृत्ति को बदलने की दिशा में कोई कारगर कार्रवाई करे, ताकि आगे से बुधनी व सुल्तानपुर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

—सुधीर सक्सेना

छाया: आर०सी० साहू

तफ्तीश : उपपुलिस निरीक्षक आरआर नेगी

अपने गिरेबां में झांकने की न तो पुलिस की आदत है और न ही मानवीयता से कोई सरोकार। कम-से-कम राजधानी के समीप रायसेन जिले के सुल्तानपुर गांव में हुए घटनाक्रम से तो यही लगता है।

कठोर कार्रवाई : आईजी एनएन विरमानी

आप इनमें से किस पुरुष जैसे दिखते हैं?

खुद को ताकतवर "ही-मैन" जैसा बनाइए. सिर्फ १४ दिनों में बेहतर नतीजे पाइए वर्ना पैसा वापस.

सांस रोककर और अपनी पेशियां फुलाकर आप शीशे में अपना शरीर देखकर आसानी से गलतफस्मी पाल सकते हैं. लेकिन आप सचमुच अपना शरीर कैसे बना सकते हैं? क्या आपके पास वैसा हृष्ट पुष्ट शरीर है जिसे देखकर पुरुष ईर्ष्या करें और स्त्रियां तारीफ करें? अगर नहीं, तो आपके लिए खुशखबरी है. पश्चिम जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नए और क्रांतिकारी बॉडी बिल्डर में प्रयोग किए गए सिद्धांतों का परीक्षण कर लिया है. यह इस ढंग से बनाया गया है कि चंद हफ्तों में ही अपने मनचाहे ढंग का व्यक्तित्व पा जाएंगे आप.

इस्ताफ सरीखी मजबूत पेशियां, चौड़ी और मजबूत छाती, शक्तिशाली कंधे, जांघें भारी और बेहद मजबूत! ये सिर्फ सपना नहीं है. इसे आप सच्चाई में बदल डालिए, रोजाना सिर्फ पांच मिनट देकर.

आखिर क्या है ये जादुई नया व्यायाम-साधन?

इसका नाम है बुलवर्कर-३, जिसमें जादू जैसी कोई बात नहीं है. ये तो बस आइसोटानिक आइसोमेट्रिक के नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधरित है जिनकी बदौलत आपके पूरे शरीर में एक नई ताकत, एक नई स्फूर्ति भरी जा सकती है — वो भी आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से कई गुना ज्यादा तेजी से, और आप खुद पर आजमाकर साबित कर सकते हैं, सिर्फ १४ दिनों में.

आपकी उम्र चाहे जो हो, आपका काम और आपकी शारीरिक स्थिति चाहे जैसी हो, बुलवर्कर तेजी से आपके शरीर को सुगठित आकार देकर उसमें ताकत ले आता है, हजारों लागों ने इसे आजमाया और अपनाया है.

भूतपूर्व 'मिस्टर युनिवर्स' मैन मैन दिखा रहा है बुलवर्कर-३ की मात्र सेकंड वाली कुछ कसरत जो शरीर में ताकत भर देता है

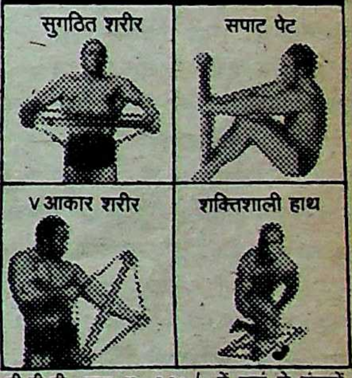

वी.पी.पी. द्वारा रु. ३२५/- में यहां से मंगायें बुलवर्कर प्रा. लि., मेहता महल, १५ मैथ्यू रोड, बंबई ४०० ००४

और सभी प्रमुख स्पोर्टर्स शॉप में भी.

ABHA

बुलवर्कर-३ देता है ५ साल की पक्की गारंटी और साथ में...

- वर्जिशें दर्शानेवाला सचित्र दीवार-चार्ट
- आहार व ट्रैनिंग-गाइड और
- कैरिंग केस

यह कूपन आज ही भेजिए

बुलवर्कर प्रा.लि. 15 मैथ्यू रोड बम्बई- 400 004.

कृपया 14 दिनों की आजमाइश के अन्तर्गत मेरा बुलवर्कर-3 मुफ्त उपहार के साथ भेज दीजिए यदि में पूर्णतया परिणामों से सन्तुष्ट नहीं हुआ तो आजमाईश अवधि के अन्दर अपनी रकम (डाक व अतिरिक्त खर्च काटकर) वापिस पाने के लिए शीघ्र ही सबकुछ लौटा दूँगा. BW-905

कृपया उचित चौकोर में ☑ निशान लगाइए

☐ रजि पोस्ट पार्सल द्वारा भेज दीजिए मैं रु. 325/- का ड्रॉफ्ट/आइ.पी.ओ./मऑ नं. .... ता............ (देय बुलवर्कर प्रा. लि. के नाम) भेज रहा हूँ. MY-60

☐ वी.पी.पी. द्वारा भेज दीजिए. डिलीवरी के समय डाकिए को रु. 325/- देने का वचन देता हूँ.

नाम ....

पता ....

....

पिन .... हस्ताक्षर ....

पर्यावरण

मजदूरों में खुलकर बढ़ रही है बीमारी

मध्यप्रदेश में विकास की रफ्तार भले ही धीमी हो, किंतु प्रदूषण की रफ्तार कतई धीमी नहीं है। तेजी से हो रहे निर्वनीकरण, शहरों के अनियोजित विस्तार और कल-कारखानों ने पर्यावरण की दुर्गति में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। बीत गये वे दिन जब मध्यप्रदेश में विपुल वन मौजूद थे। घने जंगल अब महज स्मृतियों, किस्सों और पोथियों में सिमट कर रह गये हैं। कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो गैरसरकारी तो क्या, सरकारी उपक्रम भी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आये हैं।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को ही लें। सारणी में मंडल का ताप बिजलीघर है। वहां ६२.५ मेगावाट क्षमता के जेनरेटरों से सौ टन राख प्रतिदिन उड़ती थी। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस राख ने पर्यावरण का चेहरा कितना जर्द और बेआब किया होगा। इसी प्रकार कोरबा में भी मंडल के बिजलीघरों ने पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचायी। वहां प्रदूषण की रोकथाम के लिये राखड़ बांध बनाया गया, मगर हुआ यह कि कुछ समय बाद बांध में दरार पड़ गयी, जिसके फलस्वरूप जल-प्रदूषण की घटना घटी। हायतोबा मची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वोरा ने मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव और मंडल के अध्यक्ष के साथ दौरा किया और कोडिया स्थित बांध को रिसदा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कोरबावासियों के अनुसार जल-प्रदूषण से फसलों और नागरिकों, दोनों को नुकसान हुआ। ऐसे ही रायपुर-भिलाई मार्ग पर स्थित कुम्हारी में 'द मोरार जी केमिकल्स' की फैक्टरी से उत्सर्जित पदार्थों से भी कई गांवों में फसलों को क्षति पहुंची है। मंदसौर में स्लेट पैंसिल कारखानों से निकली धूल से सिलिकोसिस नामक बीमारी की खबर को लेकर पत्र-पत्रिकाओं में खूब होहल्ला मच चुका है। किंतु खबर है कि ये कारखाने आज भी मजदूरों में खुले हाथों बीमारी बांट रहे हैं। प्रदेश के प्रदूषणकारी उद्योगों में कल तक नागदा और आमलाई के कारखानों की प्रमुखता से चर्चा होती थी। लेकिन अब सरकार का दावा है कि उनके कानों पर जूं रेंगी है।

कुछ साल पहले 'फोर्ड फाउंडेशन' ने अपनी रपट में लिखा था कि वन विकास निगम का अमला और ढांचा सामाजिक वानिकी की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिये सक्षम व उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण को लेकर कमोबेश यही स्थिति प्रदूषण निवारण मंडल की है। एक तो विकलांग ढांचा ऊपर से नीयत में खोट। हश्र यह हुआ कि मंडल जन्म के कई साल बाद तक लुंज-पुंज रहा। रही सही कसर सरकार के सौतले बर्ताव ने पूरी कर दी। गत वर्ष मंडल ने तीन करोड़ रुपयों के प्रस्ताव बनाए थे और आवास व पर्यावरण विभाग ने भी प्रथम चरण में एक करोड़ रुपए देने का वित्त विभाग से आग्रह किया था। लेकिन मंडल को ७० लाख रु० की राशि काफी नुक्ताचीनी के बाद मिली।

पर्यावरण की चिंता : महेश जोशी

पहलकदमी : मंडल के कामों में तेजी और जान तब आई, जब सन् '८५ में महेश जोशी ने आवास एवं पर्यावरण विभाग का क़ाम संभाला। जोशी ने छापामार शैली में आकस्मिक दौरों से प्रदूषणकारी उद्योगों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने ग्वालियर रेयान, नागदा, नवीन केमिकल्स, एमकेएम फैब्रिक्स एवं टाटा एक्सपोर्टस देवास, डीएमसी कुम्हारी सेंचुरी सीमेंट मांढर, जयबजरंग सीमेंट प्लांट व स्ट्रा प्लांट जगदलपुर, बेलाडिला आयरन संयंत्र, एसीसी सीमेंट, जामुल एवं कैमूर, मैहर सीमेंट वर्क्स, सतना सीमेंट, सीसीआई सीमेंट नवागांव, विक्रम सीमेंट मंदसौर, एचईजी, ओसवाल प्रोटीन, यूनाइटेड सोया मंडीदीप, ब्रुक बांड पेपर मिल व मध्यभारत पेपर मिल, बिलासपुर, सीसीआई अकलतरा तथा रतलाम और कोरबा के उद्योगों का मुआयना किया। बस्तर में वह बेलाडिला तक गये और देखा कि उत्सर्जित लौह अयस्क ने शंखिनी व डंकिनी नदियों के पानी को किस कदर प्रदूषित कर दिया है। यह आकस्मिक मुआयनों का ही नतीजा था कि रतलाम के उद्योगों, ग्वालियर रेयान नागदा, नवीन केमिकल्स, टाटा एक्सपोर्ट, एसकेएम फैब्रिक्स देवास, भिलाई इस्पात संयंत्र, सेंचुरी सीमेंट, एचईजी मंडीदीप, अमलाई पेपर मिल, मैहर सीमेंट के खिलाफ मामले दर्ज कर उन पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बरतने के लिए दबाव डाला गया। और तो और एमपीईबी को भी नहीं बख्शा गया। इस अवधि में जलप्रदूषण अधिनियम के तहत ६५ और वायुप्रदूषण अधिनियम के तहत १९ उद्योगों के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

आंख की किरकिरी : पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के फेर में जोशी अनेक उद्योगपतियों की आंख की किरकिरी भी बने। कमांड एरिया में किसी भी कीमत पर उद्योग लगाने की अनुमति न देने और सीमेंट कारखानों जैसे वायुप्रदूषणकारी उद्योगों को आबादी से दस किमी की परिधि में नहीं लगाने देने के फैसलों से 'धनिक लाबी' नाराज मी हुई। महेश जोशी को लानतें मिलीं। किंतु बाघ की गुफाओं के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उन्होंने वंदना सीमेंट को वहां फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी। यही सलूक करीब ६५ लाख रुपए खर्च कर चुकी मांडू डिस्टिलरी के साथ किया गया। सोन नदी के तट पर ८० लाख रुपए की लागत से शासकीय आसवनी बनाने का प्रस्ताव था। पूर्व आबकारी मंत्री रामकिशोर शुक्ल प्रस्ताव के पक्ष में थे, मगर पर्यावरण मंत्री आड़े आ गये। काबीना मंत्री और राज्य मंत्री के इस द्वंद्व में राज्य मंत्री जोशी ने बाजी मार ली और सोन नदी क़ा पानी दूषित होने से बच गया। बहुतों ने इसे सनक कहा, मगर उन्होंने उद्योगों को उस क्षेत्र में भेजने की नीति के अंतर्गत पेट्रोकेमिकल कारखाने को सीहोर भेज दिया।

भविष्य : ऐसा नहीं है कि इन सब उपायों से अब मध्यप्रदेश में पर्यावरण पूर्णतः सुरक्षित हो गया है। चांदी की थैली आज भी बहुधा मनचाहे फैसले लिखा लेती है। आज भी निष्पक्ष आकलन करें तो पर्यावरण को बचाने के उपक्रमों पर पर्यावरण विनाश के उपकरण भारी पड़ेंगे। राहत की बात इतनी है कि सरकार देर से ही सही, मगर चेती है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटित 'इफ्को' को भी चाकचौबंद करने की ओर ध्यान गया है। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सराहनीय काम करनेवाले उद्योगों को एक लाख रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। इस दिशा में शोध के लिए डा० प्रतापसिंह बिसेन को शासन ने इंदिरा गांधी फेलोशिप दी है। इस बीच नेतृत्व परिवर्तन के बाद आवास एवं पर्यावरण विभाग जोशी के बजाय विष्णु राजोरिया के हाथों में पहुंच गया है। किसी मंत्री का जिद्दी होना बहुतों को नागवार गुजर सकता है, किंतु यदि इसी जिद से पर्यावरण की रक्षा होती हो, प्रदूषण पर अंकुश लगता हो और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवरता हो तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकहित में राजोरिया भी अपने पूर्ववर्ती मंत्री की जिद और अड़ियलपन को बरकरार रखेंगे।

सुधीर सक्सेना

रशीद हत्याकांड

हेगड़े की दोहरी मुसीबत

केरल के एक वकील एमए रशीद की तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन पर मिली लाश ने इतना तूल क्यों पकड़ा कि कर्नाटक की हेगड़े सरकार हिल उठी, सिंचाई मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री हेगड़े को अपने गृहमंत्री का इस्तीफा मंजूर करना पड़ा?

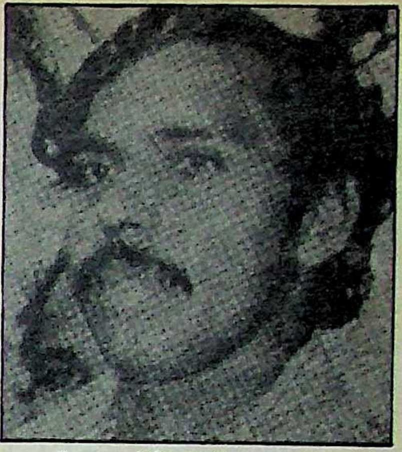

हत्या से राजनीतिक संकट: एमए रशीद

जांच की निष्पक्षता पर संदेह: रामकृष्ण हेगड़े

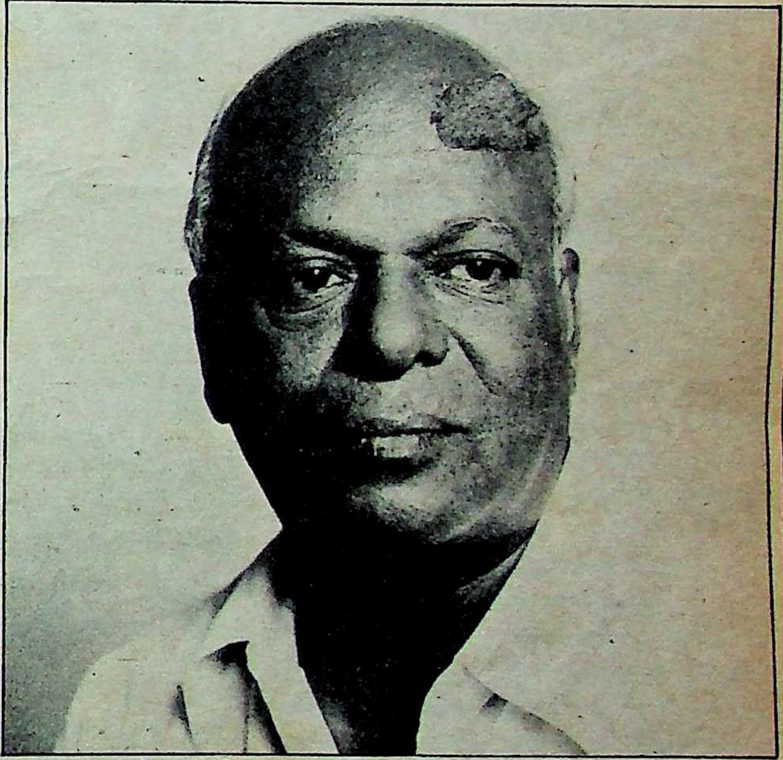

जमानत के लाले पड़ गये: आरएल जालप्पा

केरल के एक युवा वकील एमए रशीद की बंगलौर में हुई कथित हत्या के मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय दिन-प्रतिदिन उलझती जा रही है। इस हत्या में राज्य के गृहमंत्री (जिन्होंने अब त्याग पत्र दे दिया है) आरएल जालप्पा के हाथ होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि रशीद अपने मुवक्किल के किसी केस के संबंध में बंगलौर आये थे, जहां हाईग्राउंड पुलिस ने उन्हें १४ अगस्त, १९८७ को संजय गांधी बीएड कालेज के प्राचार्य की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन न्यायालय में रशीद की जमानत हो गयी और पुनः १७ अगस्त को अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी हुए। रशीद जब १७ अगस्त को न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, तो उनके नाम वारंट जारी हो गया, परंतु १८ अगस्त को उनकी लाश तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन की पटरियों के निकट क्षत-विक्षत अवस्था में मिली।

बताया जाता है कि १५ अगस्त, १९८७ को रशीद ने नगर के प्रमुख दो अखबारों के कार्यालय में जाकर यह शिकायत की थी कि उन्हें हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में बुरी तरह मारा-पीटा गया। रशीद की इस शिकायत से नाराज पुलिस ने जमानत पर छूटे रशीद को फिर से १६ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनकी लाश ही बरामद हुई। इस घटना ने ३० अगस्त को तब जोर पकड़ा, जब बंगलौर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दो दिनों तक न्यायालयों का बहिष्कार किया। एसोसिएशन ने गृहमंत्री जालप्पा पर रशीद की हत्या में 'उनका हाथ' होने का आरोप लगाया। संघ ने गृहमंत्री के त्यागपत्र की भी मांग की, परंतु मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का आश्वासन जरूर दिया और बाद में उन्होंने सीबीआई को जांच सौंप भी दी। इस प्रकार, सीबीआई की जांच के आदेश के साथ ही मामला ठंडा पड़ गया था।

राज्य में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री एचडी देवेगौड़ा ने २८ अप्रैल को जैसे ही त्याग पत्र दिया, वैसे ही कर्नाटक जनता पार्टी सरकार पर संकट के बादल घिर आये थे। मुख्यमंत्री हेगड़े इस संकट से जूझने की तैयारियों में जुटे थे। ३ मई को जनता विधायक दल की बैठक में कुछ 'विशेष' होने की चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में आम थी। ठीक ऐसे मौके पर महीनों से शांत बैठी सीबीआई हरकत में आयी और जनता विधायक दल की संभावित बैठक के एक दिन पूर्व उसने पुलिस उपायुक्त के नारायण को गिरफ्त में ले लिया। इसके पूर्व ६ पुलिसकर्मियों को तो हिरासत में काफी पहले ही ले लिया गया था। पुलिस उपायुक्त की गिरफ्तारी ने मामले में 'आग में घी' का काम किया। सुप्त पड़ा केस फिर से जनता की नजरों का केंद्र बना। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने के नारायण पर चार्ज लगाया है कि रशीद की हत्या का षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा रचा गया था। के नारायण के ऊपर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से झूठे वक्तव्य

दिलवाने, सेलम से जांच के लिए आयी पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच कार्य न करने जैसे कई आरोप सीबीआई द्वारा पुलिस उपायुक्त पर लगाये गये। नारायण की ओर से उनके वकील ने अब तक जमानत की कई अर्जियां दाखिल की हैं, परंतु न्यायालय द्वारा हर बार ये अर्जियां खारिज कर दी गयीं। १३ मई को राज्य सरकार ने पुलिस उपायुक्त नारायण को निलंबित कर दिया। नारायण इस समय सीबीआई की कस्टडी में हैं।

गृहमंत्री घेरे में: ३ मई, १९८८ से ही गृहमंत्री जालप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिये थे, किंतु उन्हें १२ मई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत की मंजूरी दी। इसके पूर्व ७ मई को सेशन जज ने जालप्पा की अग्रिम जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। यह राज्य की राजनीति में अपने ढंग का पहला मामला था, जिसमें गृहमंत्री को जमानत के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे थे। रशीद की हत्या के मामले में विवादों से घिर जाने पर जालप्पा ने पद से त्याग पत्र देना बेहतर समझा और ७ मई को वह गृहमंत्री के पद की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गये।

पूर्व गृहमंत्री जालप्पा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने और उन्हें राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही रशीद हत्याकांड में उन्हें लपेटा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेगड़े ने भी जालप्पा को केस में घसीटने के पीछे केंद्र के षड्यंत्र की बात कही। रशीद की हत्या में जालप्पा की कोई भूमिका थी या नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, परंतु सीबीआई द्वारा गिरफ्त में लिये गये १६ कथित अपराधियों में से ७ पुलिसकर्मियों का होना, गृहमंत्री की अग्रिम जमानत को सप्ताह भर मंजूरी न मिलना, गृहमंत्री का बाद में त्यागपत्र देना जैसी घटनाओं से राज्य में जनता पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक स्तर पर उसकी दखलंदाजी तथा सत्ता और पुलिस की मिली-भगत आदि का जायजा मिलता है।

११ मई को राज्य विधान सभा में इस मुद्दे पर हुई तीन घंटे की बहस में विपक्षी पार्टी कांग्रेस-इ ने मुख्यमंत्री हेगड़े से त्यागपत्र मांगा। विपक्ष का कहना था कि वकील की हत्या के लिए नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। विपक्षी मांग को हेगड़े ने न केवल नामंजूर कर दिया, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए स्पष्ट कहा कि रशीद हत्याकांड की जांच में कांग्रेस-इ की सीधी दखलंदाजी है और वह केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रही है। हेगड़े ने कहा, "२४ अगस्त को सेलम में रशीद की लाश मिली, जिसकी जानकारी २७ अगस्त को राज्य सरकार को हुई और सरकार ने तत्काल सीआईडी द्वारा जांच के आदेश दे दिये। ३० अगस्त को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह को पत्र लिखकर सीबीआई द्वारा जांच करवाने की पेशकश की। ऐसी स्थिति में भला मुख्यमंत्री त्यागपत्र क्यों देगा, जब उसकी कोई गलती ही नहीं है।"

पुलिस अफसर हिरासत में: सीबीआई अधिकारियों से घिरे पुलिस उपायुक्त के नारायण

मुख्यमंत्री हेगड़े ने तो मामले को और भी उलझा दिया है। हेगड़े ने सदन के समक्ष बयान दिया कि जो लाश सेलम के निकट रेल पटरियों पर मिली, वह रशीद की थी भी या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए रशीद की वास्तव में हत्या हुई भी या नहीं, अभी कहना कठिन है। पोस्टमार्टम दो बार होने के बाद भी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मरनेवाला व्यक्ति किन्हीं अन्य कारणों से मरा या उसकी हत्या हुई थी। मृतक की पहचान उसकी लाश के नजदीक पड़ी डायरी के आधार पर की गयी थी, जिसमें रशीद के घर का पता लिखा हुआ था।

इधर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच ने भी एक नाटकीय मोड़ लिया। जिस होटल में रशीद की हत्या होने की आशका है, उसके वाचमैन श्रीनिवास ने न्यायालय में लिखित वक्तव्य देते हुए कहा कि वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर जाते ही उसे सीबीआई वाले पकड़ लेंगे, जिनसे उसे अपनी जान का खतरा है। इसके पूर्व न्यायालय ने वाचमैन की जमानत की अर्जी मंजूर कर दी थी। श्रीनिवास ने यह वक्तव्य देकर अचंभित कर दिया कि उसने किसी भी वकील के माध्यम से जमानत की अर्जी प्रस्तुत ही नहीं की थी। श्रीनिवास ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसका एकमात्र वकील एस रामाराव है और उन्होंने ऐसी कोई अर्जी दाखिल नहीं की थी। वाचमैन ने यह भी कहा कि जब उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो वालों से जान का खतरा है, तो वह जमानत पर रिहा होकर मुसीबत मोल क्यों लेगा? वकील रामाराव ने श्रीनिवास की तरफ से यह दरख्वास्त भी की थी कि २३ मई को जमानत मंजूरी के जो आदेश दिये गये हैं, उन्हें वापस ले लिया जाये। रामाराव ने पुलिस में इस आशय की एक शिकायत भी दर्ज करायी है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो २५ मई को उनके मुवक्किल श्रीनिवास का अपहरण कर कहीं अज्ञातस्थान पर ले गयी है। उधर श्रीनिवास ने सेशन कोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग भेजे गये तारों में लिखा है कि वह स्वेच्छा से मद्रास पहुंच गया है और उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो के मद्रास कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, जो कि जमानत की एक शर्त थी। एकडवोकेट रामाराव ने न्यायालय में जमानत स्थगित करने के लिए जो अर्जी दी थी, उसे न्यायमूर्ति टीपी नांबियार ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यदि श्रीनिवास जमानत नहीं चाहते, तो स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर इस आशय की अर्जी दाखिल करते कि उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाये, वह जेल में रहना चाहते हैं।

बहरहाल, केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी जांच जारी रखे हुए है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक जो कदम उठाये हैं, उनसे राज्य में सत्तासीन जनता पार्टी की छवि पर आंच आयी है। मुख्यमंत्री अपने सहयोगी पूर्व गृहमंत्री जालप्पा की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। वह तो जालप्पा का त्यागपत्र भी लेने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु हालात ने उन्हें यह सब स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया। जालप्पा को संरक्षण देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि सीबीआई की निष्पक्षता पर भी संदेह की उंगली उठाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को उन्होंने पक्षपात पूर्ण बताया है, जबकि अभी परिणाम आने बाकी हैं।

—श्रीकांत पाराशर

जुलाई प्रथम १९८८

गृहशोभा

पंच सितारा व्यंजन विशेषांक

महानगरीय पंच सितारा होटलों के पाक-कला विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत—

७५ लजीज व्यंजन विधियां बनाने में सुगम, खर्चीली भी कम

पंच सितारा होटलों से प्राप्त चुने हुए ७५ सुस्वादु व्यंजनों की ऐसी आसान और कम खर्चीली विधियां जिन्हें आप जब चाहें घर में ही बना कर अपने परिवार और मेहमानों का दिल जीत लें

प्रमुख आकर्षण :

आवरण कथा :

अश्लील हरकतें और फिकरेबाजी : कैसे बचे नारी ?

छात्रा हो गृहणी हो या कामकाजी महिला, सभी का पाला सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे तमाम रोमियों से पड़ता है, जिनके अश्लील फिकरों और हरकतों को उन्हें झेलना पड़ता है। प्रायः महिलाएं ऐसी स्थिति में चुप रह जाती हैं, पर क्या इससे समस्या हल हो जाती है ? महिलाओं को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये ?

उपयोगी लेख :

- **समझौता हमेशा पत्नी ही क्यों करे ?**
- **कैसे बच सकती हैं आप अलसर से ?**

साथ ही सभी स्थाई स्तंभ

मूल्य
रु० ६/-

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराइये

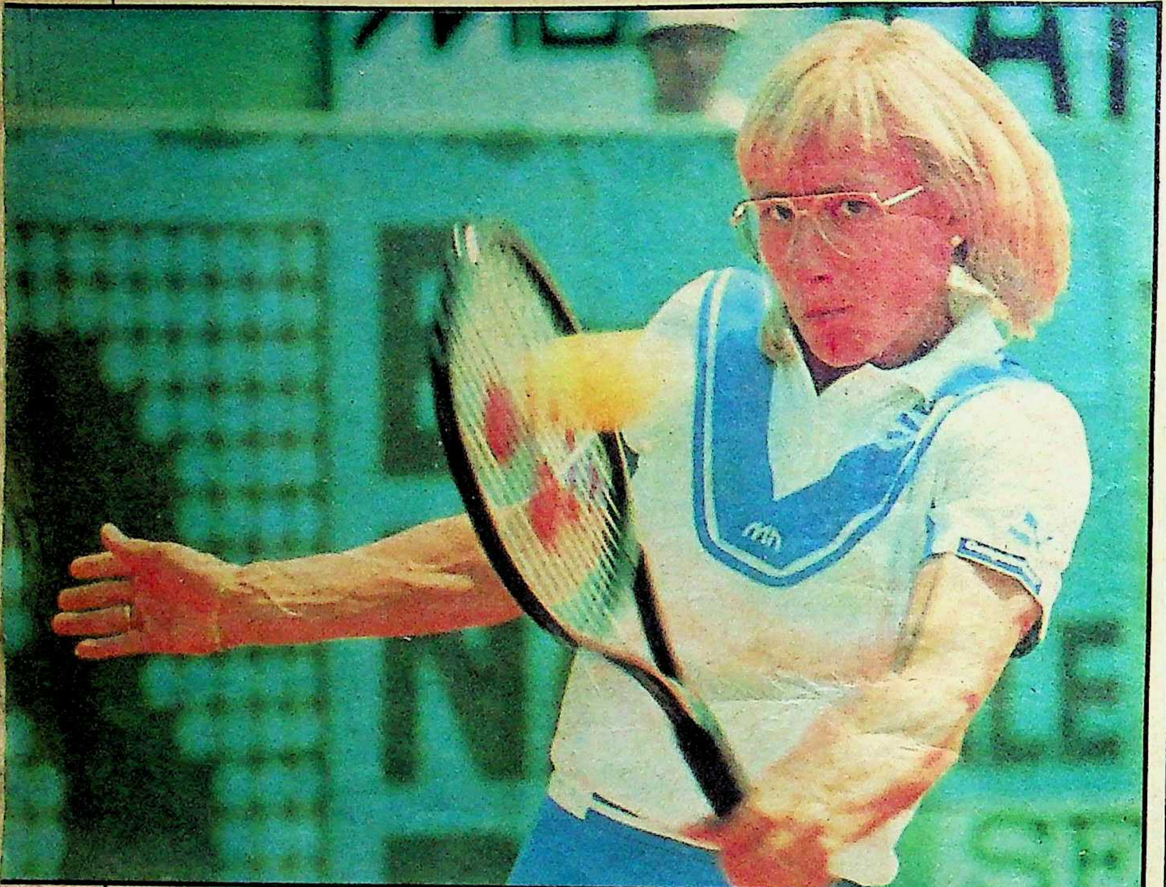

एक दशक तक छायी रहीं: मार्टिना नवरातिलोवा

महिला खिताब की नयी दावेदार: स्टेफीग्राफ

विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता

जीत का सेहरा किसके सिर ?

दुनियाभर के टेनिस प्रेमी हर साल जिस महीने का बेकरारी से इंतजार करते हैं, वह फिर आ धमका है। विश्व के चुने हुए, ग्लैमर वाले खिलाड़ियों के साथ विंबलडन टेनिस प्रतियोगिताएं इस साल भी धूमधाम से होंगी। पर, अबकी बार जीतेगा कौन? किसको कौन-सा खिताब मिलेगा? और विंबलडन के सौ वर्षों के इतिहास में अब तक किस-किसने कैसे-कैसे करतब दिखाये हैं? एक लेखाजोखा:

सारे संसार के टेनिस प्रेमी हर वर्ष जुलाई का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिताओं का अंतिम दौर होता है। यों तो साल में अनेक विश्व स्तरीय टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन विंबलडन में विजयी खिलाड़ी ही सही मायने में विश्व-विजेता माना जाता है। यही कारण है कि विंबलडनं को टेनिस का 'मक्का' कहा गया है।

शुरुआत: विंबलडन ब्रिटेन के दक्षिण-पूर्वी राज्य सरे में स्थित एक सुंदर शहर है। १८७७ में विंबलडन की अखिल इंग्लैंड क्रिकेट और टेनिस क्लब नामक संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर एक टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन का बीड़ा उठाया था। उन दिनों ब्रिटेन में टेनिस को केवल वक्त काटने के लिए खेला जाता था। प्रतिस्पर्धा की भावना खेल में नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती गयी, खेल का स्तर भी उठता गया।

विंबलडन में महिला खिलाड़ियों का प्रवेश १८८४ में हुआ। प्रथम महिला विजेता बनीं—कुमारी माड वाटसन। लेकिन, पुरुष खिलाड़ियों जैसी व्यावसायिकता महिलाओं में नहीं थी। वे

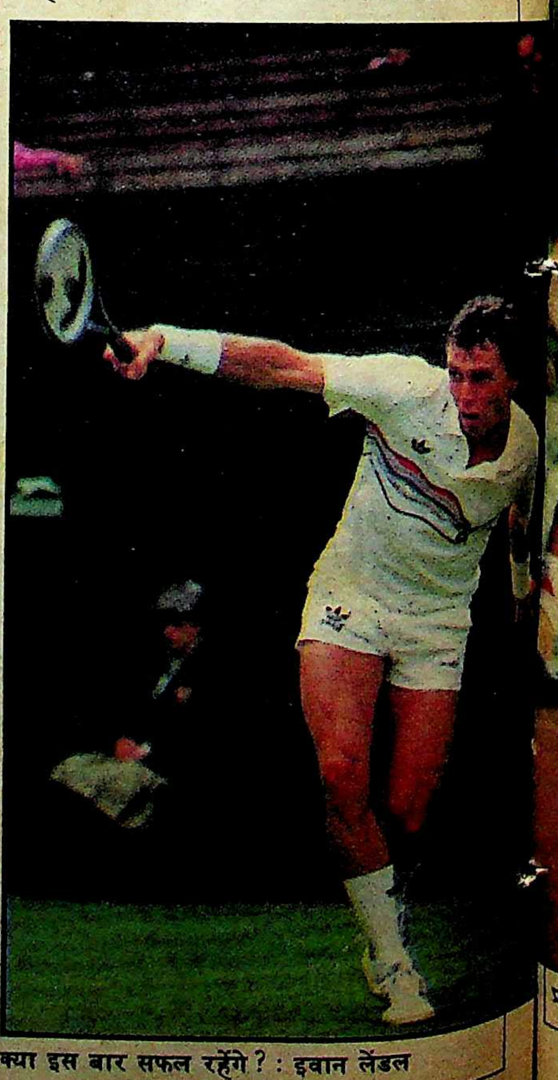

क्या इस बार सफल रहेंगे? : इवान लेंडल

ग्लैमर और कला का संगम : सबातिनी

अक्सर रंग-बिरंगे कपड़े और टोपी पहने मैदान में उतरती थीं। ऐसा लगता था कि किसी मेले के लिए सजी हों। १८६१ में कुमारी डोड ने विंबलडन में कम लंबाई की स्कर्ट और कमीज पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। यह कहना गलत न होगा कि कुमारी डोड विंबलडन की पहली 'ग्लैमर' खिलाड़ी हैं।

पहले अट्ठारह वर्षों में विंबलडन में केवल ब्रिटेन के खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता १८६५ से शुरू हुई और विश्व के अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेने लगे।

व्यावसायिकता : बीसवीं संदी के आरंभ से टेनिस जगत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी ही थी, बहुत से खिलाड़ियों ने खेल को अपना व्यवसाय बना लिया था। परंतु ऐसे खिलाड़ियों को विंबलडन में नहीं खेलने दिया जाता था। यही कारण है कि आस्ट्रेलिया के राड लेवर, जिन्होंने १९६१ और १९६२ में पुरुषों के एकल का खिताब जीता था, को १९६३-६७ तक विंबलडन में खेलने नहीं दिया गया, क्योंकि उस दौरान वह एक व्यावसायिक खिलाड़ी बन चुके थे। १९६८ में पहली बार व्यावसायिक खिलाड़ियों को विंबलडन में खेलने दिया गया। राड लेवर उस वर्ष बाजी मार कर विंबलडन के ऐसे प्रथम विजेता बने, जो व्यावसायिक खिलाड़ी भी थे।

उन दिनों रंगभेद नीतियों का बोलबाला था और उसके विरोध में आवाजें भी उठ रही थीं। उन नीतियों के कारण कई अच्छे खिलाड़ियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। ऐसी ही एक खिलाड़ी थीं, अमरीका की कुमारी गिब्सन। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थीं, लेकिन अश्वेत होने के कारण उन्हें विंबलडन में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तब, अमरीका की एक पत्रिका ने अपने लेखों में गिब्सन को विंबलडन में खेलने की सिफारिश करते हुए रंगभेद नीतियों पर चोट की। इन लेखों से जनमत बना और विंबलडन के अधिकारियों को मजबूर होकर अश्वेतों के प्रवेश पर सें रोक हटानी पड़ी। गिब्सन १९५७-५८ में विंबलडन की महिला एकल चैंपियन रहीं।

१९६६ में महिला टेनिस जगत में एक सशक्त नाम उभरा, बिलि जीन किंग का। अमरीका की किंग ने विंबलडन में छह महिला एकल खिताब, दस युगल खिताब तथा ४ मिश्रित युगल खिताब जीते। उन्होंने महिला टेनिस खिलाड़ियों को मिल रही निम्न स्तरीय सुविधाओं का विरोध किया। उन्होंने अधिकारियों का ध्यान इस बात पर खींचा कि १९६८ में जहां पुरुष एकल विजेता राड लेवर को २००० पौंड का पुरस्कार मिला था, उन्हें केवल ७०० पौंड दिये गये। यह उन्हीं के अभियान का नतीजा है कि आज विंबलडन के पुरुष एकल विजेता को जहां ३१ लाख रुपए मिलते हैं, वहीं महिला

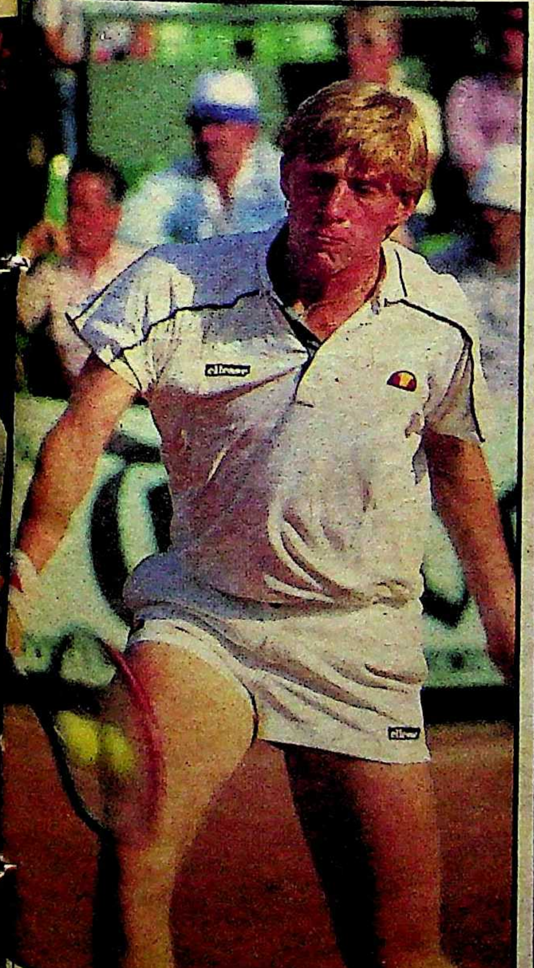

प्रतिभा की कमी नहीं : बोरिस बेकर

अभी तक जोर है : क्रिस एवर्ट

सही निर्णय का

अन्दरूनी राज़

RUPA®
Frontline
RUPA
Frontline
BRIEFS

प्रश्न जब त्वचा की सुरक्षा का है, तो सावधानी बरतने में ही समझदारी है। गलत निर्णय आपके लिये परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिये रूपा फ्रन्टलाइन ही खरीदिये और निश्चित रहिये। भारतीय जलवायु के उपयुक्त, नवीनतम तकनीक से बना रूपा फ्रन्टलाइन आपकी त्वचा को बराबर सुरक्षा देता है। शतप्रतिशत सुती धागे से बना। इसकी उत्कृष्ट फिनिश रेशम सी कोमलता का अहसास दिलाये। फिटिंग पूर्णत: आरामदायक। इम्पोर्टेड रबर से बना इलास्टिक। निराले रंगों में उपलब्ध। इन्हीं सब खूबियों के कारण रूपा फ्रन्टलाइन सही निर्णय लेने में आपका सहायक होता है।

'फ्रन्ट ओपन' की स्पेशल सुविधा
सिर्फ रूपा फ्रन्टलाइन ब्रीफ़ में

RUPA®
Frontline
BRIEFS

भारत में पहली बार, अपनी किस्म का ख़ास

विनोद होजियरी, कलकत्ता (७०० ००१) का एक उत्कृष्ट उत्पादन

UPS/BH-885

विजेता को २८ लाख रुपए। दोनो की पुरस्कार राशि में अंतर कम करने का श्रेय किंग को ही जाता है।

नये नाम: १९७० के दशक में पांच नाम विंबलडन पर छाये रहे—पुरुषों में ब्योन बोर्ग, जान मैकनरो और जिमी कोनर्स तथा महिलाओं में क्रिस एवर्ट और मार्टीना नवरातिलोवा। बायें हाथ से खेलने वाले अमरीका के कोनर्स पिछले सोलह वर्षों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन उनके स्तर में कोई गिरावट नहीं आयी है। १९७४ में उन्होंने प्रथम बार पुरुषों का खिताब जीता। लेकिन इसके बाद ब्योन बोर्ग आंधी की तरह आये और सभी खिलाड़ियों को अपनी चपेट में लेते हुए लगातार पांच वर्षों तक पुरुष एकल खिताब पर कब्जा जमाये रखे। उस दौरान कई मंजे हुए धुरंधर खिलाड़ी, जैसे आर्थर ऐश और इली नस्तासे, हमेशा के लिए बैठ गये, परंतु जिमी कोनर्स का प्रदर्शन अच्छा बना रहा। यहां तक कि १९८२ में वह फिर से विंबलडन चैंपियन बन गये।

स्वीडन के बोर्ग की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत और सौम्य व्यक्तित्व था। टेनिस खेलते वक्त उनका चेहरा एकदम सपाट रहता था। चाहे वह हारते होते, चाहे जीतते, उनके चेहरे पर कोई हाव-भाव न आता। इसलिए उन्हें 'बर्फीला' बोर्ग भी कहा जाता था। इसमें संदेह नहीं कि बोर्ग आधुनिक टेनिस इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जायेंगे। १९८१ में मेकनरो के हाथों परास्त होने के बाद उन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया।

यों तो मेकनरो बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी गुस्सैल स्वभाव रहा है। जब किसी खेल का परिणाम उनके अनुकूल नहीं नजर आता है, तो वह कभी अपने प्रतिद्वंद्वी पर, तो कभी रेफरी पर अनायास ही बरस पड़ते हैं। इस स्वभाव ने उनके खेल पर प्रतिकूल असर डाला है और यही कारण है कि वह प्रतिभा संपन्न होते हुए भी केवल दो बार ही विंबलडन में पुरुषों का खिताब जीत पाये।

क्रिस एवर्ट भी कोनर्स की ही तरह पिछले डेढ़ दशकों से विंबलडन पर छायी हुई हैं। लेकिन जब से मार्टीना नवरातिलोवा आयी हैं, एवर्ट को अकसर दूसरे या तीसरे स्थान से संतुष्ट होना पड़ता है। नवरातिलोवा जैसी महिला खिलाड़ी शायद ही कोई हुई हो। उन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब १९७८ में जीता। उसके पश्चात १९७९, १९८२, १९८४, १९८५, १९८६ और १९८७ में उन्होंने सफलता पायी।

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन: जहां तक भारतीय खिलाड़ियों का सवाल है, उनका विश्व स्तरीय टेनिस प्रतियोगिताओं में हमेशा से अच्छा प्रदर्शन रहा है। १९६०-१९७० के मध्य भारत के रामनाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, गौस मोहम्मद, नरेश कुमार जैसे खिलाड़ियों ने अपने अनूठे प्रदर्शन से टेनिस चहेतों का मन मोह लिया था। परंतु, विंबलडन में भारतीय खिलाड़ियों को सीमित सफलता ही मिली है। १९५४ में रामनाथन कृष्णन ने लड़कों की एकल प्रतियोगिता जीती थी तथा इसके २५ वर्ष बाद, १९७९ में उन्हीं के बेटे रमेश कृष्णन ने भी वही खिताब जीता। पिछले कुछ वर्षों से रमेश, विजय अमृतराज तथा आनंद अमृतराज की तिकड़ी टेनिस जगत में भारत का झंडा फहराती आयी है।

एकमात्र भारतीय उम्मीद: रमेश कृष्णन

रमेश कृष्णन के खेल की खूबी उनकी 'टच' शैली है। वह न तो जोरदार सर्विस करते हैं और न ही उनके जवाबी हमलों में अन्य खिलाड़ियों जैसी तीव्रता होती है। वह गेंद पर ऐसी कुशलता से एक नपा-तुला हलका प्रहार करते हैं कि दर्शक मंत्र-मुग्ध हो जाते हैं।

विजय विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियो में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन विंबलडन में चौथे दौर से आगे वह कभी नहीं बढ़ पाये हैं। १९७९ में ब्योन बोर्ग के खिलाफ वह दो सेटों की बढ़त हासिल कर चुकने के बावजूद हार गये तथा बोर्ग अंततः उस वर्ष के विंबलडन विजेता बने। इसी प्रकार, विजय १९८१ में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चौथे दौर में पहुंच गये थे, लेकिन जिमी कोनर्स के मुकाबले नहीं टिक पाये। १९८६ में रमेश कृष्णन भी विंबलडन के चौथे दौर में पहुंच कर परास्त हो गये।

रमेश कृष्णन के खेल की खूबी उनकी 'टच' शैली है। वह न तो जोरदार सर्विस करते हैं और न ही उनके जवाबी हमलों में अन्य खिलाड़ियों जैसी तीव्रता होती है। वह गेंद पर ऐसी कुशलता से एक नपा-तुला हलका प्रहार करते हैं कि दर्शक मंत्र-मुग्ध हो जाते हैं।

निश्चित ही यह शैली उन्होंने अपने पिता से अपनायी है। कई धुरंधर खिलाड़ी तो रमेश की इस 'नाजुक शैली' को ठीक से न समझ पाने के कारण ही उनके हाथों परास्त हुए हैं।

जीत किसकी ?: इस वर्ष के विंबलडन में किसकी जीत होगी ? अग्रणी खिलाड़ियों के पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाये, तो चेकोस्लोवाकिया के इवान लेंडल का पलड़ा भारी नजर आता है। लेंडल को १९८७ के विंबलडन फाइनल में आस्ट्रेलिया के पैट कैश से अप्रत्याशित मात खानी पड़ी थी। उनका प्रदर्शन 'अमरीकी ओपन', 'फ्रांसीसी ओपन' तथा 'आस्ट्रेलियाई ओपन' जैसी सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार रहा है। लेंडल के अलावा स्वीडन के मैट्स विलैंडर पर भी उम्मीदें बंधी हैं। विलैंडर ने हाल ही १९८८ का 'फ्रांसीसी ओपन' खिताब भी जीता है। विलैंडर और लेंडल के अलावा पश्चिम जर्मनी के बोरिस बेकर भी कमाल दिखा सकते हैं क्योंकि वह पुरुषों का खिताब १९८४ और १९८५ में जीत चुके हैं।

जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, पश्चिम जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने पिछले वर्ष प्रथम पर नवरातिलोवा का आधिपत्य समाप्त किया था। १९८८ का 'फ्रांसीसी ओपन' महिलाओं का खिताब भी उन्होंने बड़ी आसानी से जीता। वैसे यह कहना कि अब नवरातिलोवा कमजोर पड़ गयी हैं, अनुचित होगा, क्योंकि उनके खेल का स्तर अभी भी कई खिलाड़ियों से ऊंचा है और वह विंबलडन के फाइनल में पहुंचने में सक्षम हैं। इनके अलावा कुछ उभरते नाम हैं, गेब्रियेला सबातिती और हाना मांडलीकोवा। दोनों ही खिलाड़ियों से विंबलडन में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

छाया: एएफपी

—राजेश सिंह

मैंने अभी-अभी दसवीं पास की है।
मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आगे पढ़ना चाहती हूँ।
लेकिन पिताजी जल्द ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं।
क्या कोई उन्हें समझा नहीं सकता कि मैं अभी छोटी हूँ?

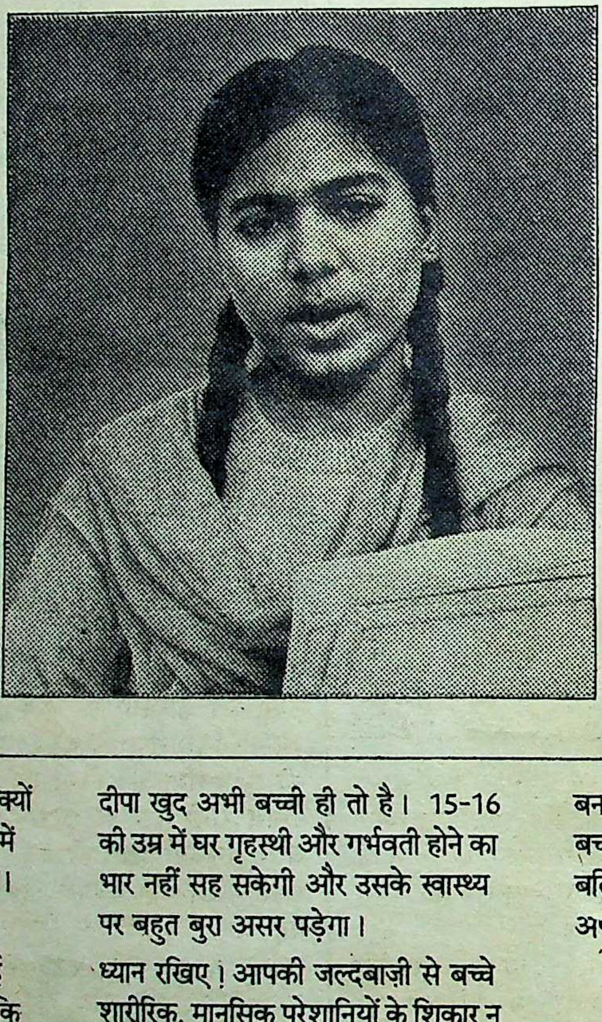

शायद दीपा स्वयं भी नहीं जानती कि वह क्यों मना कर रही है। लेकिन दीपा के मन में ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ने के सपने हैं। वह उन्हें सच करना चाहती है।

दीपा के माता पिता ज़रूर उसकी भलाई चाहते हैं लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि दीपा खुद अभी बच्ची ही तो है। 15-16 की उम्र में घर गृहस्थी और गर्भवती होने का भार नहीं सह सकेगी और उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

ध्यान रखिए! आपकी जल्दबाज़ी से बच्चे शारीरिक, मानसिक परेशानियों के शिकार न बन जाएं। यह ठीक है कि दीपा आपकी बच्ची है पर उसके फ़ैसले आप मत कीजिए बल्कि फ़ैसला करने में मदद दीजिए! उसे अपने फ़ैसले खुद लेने दीजिए।

डाक्टर की सलाह मानिए :

डाक्टरों का कहना है कि लड़की के शरीर का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता रहता है। वह 15-16 साल में जवान ज़रूर दिखती है लेकिन गर्भाशय और डिम्ब ग्रन्थियों का विकास 18 वर्ष तक होता रहता है। अगर लड़की 18 वर्ष से कम आयु में माँ बने तो ये मुश्किलें सामने आती हैं :

1. **लड़की के शरीर का विकास रुक जाता है।**
2. **18 वर्ष से कम उम्र माँ की सन्तान कमज़ोर और कम वज़न की पैदा होती है।**
3. **ऐसी कमज़ोर या कम वज़न संतान की बहुधा मृत्यु हो जाती है।**
4. **क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र में कुछ प्रजनन अंगों जैसे गर्भाशय और डिंब ग्रंथियों का विकास पूर्ण नहीं होता इसलिए अक्सर गर्भपात हो जाता है। माँ बनने में भी कठिनाइयाँ आती हैं।**
5. **पैलविस का पूर्ण विकास 18 साल से पहले नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे का सिर उसकी तुलना में बड़ा पड़ सकता है। प्रसव में बाधा से अन्दरूनी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मूत्राशय या मलाशय में कमजोरी पैदा हो जाती है।**
6. **कम उम्र में यौन-सम्बन्ध से गर्भाशय-मुख में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह भारतीय महिलाओं में कैंसर का मुख्य कारण है।**

याद रखिए:बच्ची के बच्चा होना उसके साथ घोर अन्याय है।

अठारह वर्ष से पहले लड़की और इक्कीस वर्ष से कम लड़के की शादी कानूनन अपराध है।

और जानकारी और मुफ़्त पत्रिका के लिए इस पते पर लिखिए:पोस्ट बाक्स नं. 5420 नई दिल्ली 110011

davp 88/149

शत्रुघ्न सिन्हा

कला से राजनीति में जाने की दबे मन इच्छा रखनेवाले शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे कलाकार हैं, जो छोटी-छोटी भूमिकाओं के बावजूद आज लोकप्रियता के शिखर पर हैं। भूमिकाओं में जान फूंकने की क्षमता और आवाज से भूमिका की गंभीरता को एक पहचान देने में शत्रुघ्न सिन्हा का कोई जवाब नहीं है। राजनीतिक गतिविधियों में भीतर-भीतर सक्रिय रहते हुए भी वह अभी किसी राजनीतिक मंच (पार्टी) पर खुलकर नहीं आये हैं। यह और बात है कि वह अपनी गतिविधियों से बिहार सरकार की नींद अकसर हराम कर देते हैं, क्योंकि आदिवासी तथा पिछड़े लोगों के बीच वह उनका दुख-सुख सुनने अकसर पहुंच जाया करते हैं।

जो कांग्रेस सरकार इलाहाबाद का उपचुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावनाओं को उभाड़कर दूरदर्शनी राम (अरुण गोविल) का इस्तेमाल कर रही है—उसी सरकार के प्रति शत्रुघ्न सिन्हा का आरोप है कि 'विपक्ष का समर्थक' होने का ठप्पा लगाकर केंद्र सरकार ने उन्हें ताशकंद (सोवियत संघ) अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने से वंचित कर दिया, जहां उनके द्वारा अभिनीत बंगला फिल्म 'अंतर्जली यात्रा' प्रतियोगिता खण्ड में न सिर्फ प्रदर्शित की गयी, बल्कि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि गौतम घोष द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 'गोल्डन सिमर्ग अवार्ड' भी मिला।

सरकार ने इस कदर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भेदभाव किया कि 'अंतर्जली यात्रा' को ताशकंद फिल्म समारोह में शामिल करने के बारे में कोई जानकारी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं दी। यहां तक कि सरकार ने शत्रुघ्न सिन्हा को अधिकृत निमंत्रण तक भेजने की औपचारिकता का भी निर्वाह नहीं किया।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों की परंपरा के मुताबिक वहां जानेवाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में उन फिल्मों के निर्देशक तथा प्रमुख कलाकार भी होते हैं। लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हरिकिशन लाल भगत के नेतृत्व में ताशकंद गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल में ऐसे कलाकार शामिल थे, जिनकी फिल्में समारोह में शामिल ही नहीं थीं।

सरकार कहती है कि समय पर वीसा न मिल पाने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा इस समारोह में शामिल नहीं हो सके, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वीसा संबंधी सारी बातें बहानेबाजी हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि मैं ताशकंद जाऊं और सोवियत जनता का प्यार प्राप्त कर सकूं। जब सरकार ने निमंत्रण नहीं भेजा, तो मैंने अपना प्रतिनिधि दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास में भेजा, ताकि सोवियत संघ का वीसा प्राप्त किया जा सके।

शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने 'अंतर्जली यात्रां' में अभिनय की ऊंचाई को स्पर्श किया, उस फिल्म को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा २३ मई को की गयी। चिली से निर्वासित फिल्म निर्देशक मिगुएल लितिन की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने १५ फीचर फिल्मों में से गौतम घोष की 'अंतर्जली यात्रा' को हर लिहाज से श्रेष्ठ पाया।

वैसे तो 'अंतर्जली यात्रा' एक ऐसे समाज की ओर उंगली उठाती है, जिसने एक महिला को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। 'अंतर्जली यात्रा' की कहानी परदे से उतर कर शत्रुघ्न सिन्हा के जिंदगी की इस कदर हकीकत बन गयी है कि सरकारी रवैये के चलते उन्हें ताशकंद जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

स्टेफीग्राफ

फ्रेंच ओपन टेनिस में इस बार जिस तरह का उतार-चढ़ाव हुआ, उससे एक बार लगा कि टेनिस की मानी हुई खेल हस्तियों का वर्चस्व नयी खेल हस्तियों के आगे जाता रहेगा। जिस तरह से सोवियत संघ की १७ वर्षीया नातालिया जवेरेवा ने टेनिस रानी मार्तिना नवरातिलोवा जैसी अनुभवी खिलाड़ी पर अपनी सनसनीखेज जीत दर्ज की, उससे तो यह लगा कि महिला टेनिस का समीकरण इस बार बदल जायेगा और टेनिस की नयी रानी नयी कहानी के साथ टेनिस के मंच पर अवतरित होगी। पर स्टेफीग्राफ ने सारे उतार-चढ़ाव को दरकिनार करते हुए जब ४ जून को फ्रेंच ओपन के फाइनल में नातालिया जवेरेवा को मात दी, तो टेनिस पंडितों का विश्वास बना रहा कि अभी भी स्टेफीग्राफ जैसी खिलाड़ियों से उम्मीद लगायी जा सकती है। गेब्रिएला सबातिनी से दो बार पराजित हो चुकी स्टेफीग्राफ सर्वोच्च शिखर पर पहुंच पायेगी—यह सवाल टेनिस पंडितों को मथ रहा था। मात्र ३४ मिनट के एकतरफा मुकाबले में स्टेफीग्राफ ने नातालिया जवेरेवा को बिना एक भी गेम खोये ६-०, ६-० से हराया। यह ऐतिहासिक जीत रही। फ्रेंच ओपन के ९२ साला इतिहास में ऐसा एकतरफा मुकाबला आज तक नहीं हुआ। १९२६ में फ्रांस की ही सूजन लेंडलेन ने अमरीकी मेरी ब्राउन को ६-१, ६-० से हराया था। इसी तरह, १९७९ में क्रिस एवर्ट ने भी आस्ट्रेलिया के वेंडी टर्नबुल को ६-२, ६-० से पराजित कर आसानी से विजय प्राप्त की थी। अब भविष्य में स्टेफीग्राफ के इस रिकार्ड की बराबरी ही की जा सकेगी, इसको तोड़ा नहीं जा सकेगा। यही नहीं, डोरोकी लैम्बर्ट के बाद बिना एक भी गेम गंवाये किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में विजेता होने वाली स्टेफीग्राफ पहली खिलाड़ी भी हो गयी है। इसके पूर्व १९११ में डोरोकी ने डोरा बूथवी को ६-०, ६-० से मात दे करके विंबलडन जीता था।

स्टेफीग्राफ को इस जीत से २ लाख ६४ हजार डालर इनामी राशि मिली। स्टेफीग्राफ ने जनवरी में आस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। पिछले वर्ष भी उसने फ्रेंच ओपन में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। विंबलडन और अमरीकी ओपन जीत कर वह सभी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीतने की ओर बढ़ गयी है। अब तो उसकी नजर आस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के उस इतिहास पर लगी होगी, जब उसने एक ही वर्ष में चार ग्रैंड स्लैम खिताब अपनी झोली में डालकर एक नायाब कीर्तिमान स्थापित किया था। शीर्ष पर बने रहने की यात्रा पर निकली स्टेफीग्राफ पिछले वर्ष से ही शीर्ष पर है। तीन वर्ष की उम्र में ही स्टेफीग्राफ टेनिस के मैदान पर आ गयी थी। उसके पिता पीटर ग्राफ उसके प्रशिक्षक रहें। ८ वर्ष की उम्र तक पहुंच कर वह टेनिस से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी और १३ वर्ष की उम्र में उसने विश्व टेनिस की वरीयता में अपना नाम दर्ज कर लिया था। १४ वर्ष की उम्र में उसने लास एंजेल्स ओलंपिक में भाग लिया। १७ वर्ष की उम्र में फ्रेंच ओपन जीतकर उसने शीर्ष पर बने रहने का बिगुल बजा दिया। १४ जून को १९वें वर्ष में प्रवेश कर गयी स्टेफीग्राफ जिस आत्मविश्वास और पैनेपन के साथ टेनिस-मुकाबले में संघर्ष करती है, उससे लगता है कि वह अपनी सर्वोच्चता की लंबी यात्रा तय करेगी।

—दिनेश दीप्त

गीतकार हसरत जयपुरी राजकपूर की यूनिट के एकमात्र जिंदा सदस्य हैं। नर्गिस, मुकेश, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और राजकपूर एक-एक कर बिछड़ गये।

हसरत जयपुरी

उनके गम उठाने को एक हम ही रह गये!

१९४५ की वह एक खुशनुमा रात थी। मंच पर हम सब कवि एक-एक कर अपनी कविताओं-नज्मों का पाठ कर रहे थे और पंडाल में बैठे दर्शक की तालियां वाहवाही के अंदाज में बज-बज उठती थीं। मंच पर एक अजीब शख्सीयत भी विराजमान थी। जब मैंने अपनी शायरी खतम की, तो वह उठकर मेरे पास आये और मुझे गले लगा लिया, "मैं पृथ्वीराज कपूर हूं; कभी आकर मिलो। तुम्हारी शायरी अंदाज-ए-बयां है। फिल्मों में लिखोगे, तो छा जाओगे।"

वह बात आयी-गयी हो गयी। एक वर्ष बाद १९४६ में फिर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने पहले तो न मिलने की शिकायत की, फिर सामने बैठे नीली आंखों वाले गोरे-चिट्टे एक खूबसूरत युवक से परिचय करवाया, "यह मेरा बेटा राज है। 'आग' बना रहा है। नये फनकारों को लेकर अपनी एक अलग यूनिट बनाना चाहता है। उसे कुछ अपनी नज्में सुनाओ। अल्लाताला रहेगा, तो कामयाब हो जाओगे।" सच कहूं, उस पहली मुलाकात में ही उस दिलकश चेहरे-सागर-सी गहरी, लेकिन बोलनेवाली आंखों वाले युवक राज कपूर पर मैं फिदा हो गया। मैंने उन्हें अपने कुछ कलाम सुनाये और दूसरे दिन फिर हमारा मिलना तय हुआ पृथ्वी थियेटर्स में।

पृथ्वी थियेटर्स की कैंटीन में मेरी वह मुलाकात एक तरह से सिटिंग के रूप में बदल गयी। उस समय वहां राज कपूर के अलावा शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और मुकेश भी बैठे हुए थे। पास में हारमोनियम-तबला भी रखा हुआ था। राज ने एक सिचुएशन के बारे में बतला कर शंकर से उसकी बनायी धुन सुनाने के लिए कहा। शंकर ने हारमोनियम बजाकर धुन सुनायी, तो राज टेबुल को बजाकर ही उसका ठेका निकालने लगे, फिर मुझसे बोले, "म्यां इस धुन पर एक मुखड़ा सुना दो।"

ऐसे बनी यूनिट: एक मिनट के लिए मैंने आंखें बंद कीं, फिर गुनगुनाया—***'जिया बेकरार है, छायी बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है'***। चाय—प्यालों से खनकते उस कैंटीन के माहौल में राज ने वाहवाही करते हुए कहा, "वाह! म्यां खूब सुनाया आपने। बस इसी मुखड़े पर पूरा गीत लिख डालिए।" मैं बेसाख्ता बोल पड़ा, ***'छोड़ गये बालम, मोहे हाय अकेला छोड़ गये'***। राज ने तुरंत ठेका बजाना छोड़ कर मुझे गले लगा लिया और बोल पड़े, "बस बस, हो गयी मेरी यूनिट पूरी। शंकर जयकिशन संगीत की धुनें निकालेंगे और तुम तथा शैलेंद्र उन पर गीत लिखोगे और मेरे गाने गायेंगे मुकेश। म्यां तुम इन दोनों मुखड़ों पर गीत तैयार कर चौथे दिन सेंट्रल स्टूडियो में सभी के साथ मिलोगे। वहीं बैठकर सुनेंगे, फिर बाद में गानों की रिकार्डिंग कर लेंगे।"

शुरू से अंत तक का साथ: 'हिना' की रिकार्डिंग के समय लता मंगेशकर और राज कपूर

चौथे दिन हम लोग सेंट्रल स्टूडियो में इकट्ठा हुए, जहां राज महबूब साहब की फिल्म 'अंदाज' की शूटिंग कर रहे थे। वहीं उन्होंने महबूब साहब व दिलीप कुमार से, जो उन दिनों सुपर स्टार थे, हमारा तवार्रुख करवाया और फिर नर्गिस व लता मंगेशकर से मिलवाया। लता तब नयी-नयी आयी थीं और संगीतकार नौशाद ने 'अंदाज' के लिए उनसे बेहतरीन गाने गवाये थे, लताजी का तवार्रुख करते हुए बोले, "हमारी यूनिट की एक और नयी सदस्या हैं लताजी जो हीरोइन के सारे गाने गायेंगी—'बरसात' में भी और आगे की फिल्मों में भी।" फिर वह नर्गिसजी की तरफ मुड़कर एक विशेष दिलकश अंदाज में मुसकराये, "और हमारी सारी फिल्मों की हीरोइन तो यही रहेंगी...।"

स्व० शैलेंद्र मुझसे पहले राज कपूर की यूनिट में आ चुके थे। वह 'इप्टा' (इंडियन पीपुल्स थियेटर) से जुड़े हुए थे और रेलवे में मुलाजिम थे। कम्युनिस्ट खयालात के होने के कारण बर्तानवी हुकूमत ने न केवल उन्हें सिर्फ नौकरी से निकाला, बल्कि रेलवे क्वार्टर से भी बेदखल कर दिया था। और उसी दौर में वह राज के निकट आ चुके थे। मेरे आने से पहले उन्होंने 'बरसात' के लिए दो गाने—***'बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम'*** व ***'तिरछी नजर है पतली कमर है'*** लिख चुके थे। मुकेश से भी राज की पहले से दोस्ती थी।

घरेलू संबंध: राज कपूर यूनिट ज्वाइन करने के पूर्व हम सभी पृथ्वी थियेटर्स में नौकर थे, लेकिन नौकर से ज्यादा हम परिवार के सदस्य थे। राज कपूर ने जब हमें अपनी यूनिट में लिया, तो काम के अनुसार सभी को पारिश्रमिक का भुगतान एडवांस में ही कर दिया। 'बरसात' के निर्माण के बाद उन्होंने हम सभी को मासिक वेतन पर नियुक्त कर दिया। यद्यपि इसमें राज कपूर को नुकसान था, क्योंकि उनकी एक फिल्म बनने में डेढ़ से तीन वर्ष तक लग जाया करते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि हम लोगों को तकलीफ हो।

राज जब भी खाली होते, तो हम लोगों को सिटिंग के लिए बुला लेते, नहीं तो हम लोग शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में रोजाना इकट्ठा होकर नयी-नयी धुनों पर काम करते। 'बरसात' हिट होने के बाद शंकर जयकिशन ने एक जगह लेकर उसे म्यूजिक रूम बना दिया था। जब लोनी (लोनावाला) में राजकपूर ने राज बाग

बनवाया, तो वहां भी एक म्यूजिक रूम बनवा दिया और वहीं हम लोग इकट्ठे होने लगे। राज कपूर ने जब आरके स्टूडियो की स्थापना की, तो वहां अलग से एक विशेष म्यूजिक रूम बनवाया, जहां हम सब इकट्ठा हो काम करते थे। वह खाली होते ही वहां आ पहुंचते और धुनें सुनते तथा फाइनल करते। वह सिर्फ सुनकर ही फाइनल नहीं कर देते, बल्कि एक-एक प्वाइंट पर राग और ताल से लेकर म्यूजिक पीस तक पर बड़ी बारीकी से बहस करते। वह संगीत के मास्टर थे। बहुत से सुपरहिट गीतों के मुखड़े और धुनें उन्हीं की बनायी हुई थीं। 'राम तेरी गंगा मैली' का गीत ***'सुन साहिबा सुन'*** के बोल तथा धुन उन्हीं की बनायी हुई थी।

राज के काम करने का तरीका ही अलग था। उन्होंने शंकर जयकिशन तथा मेरी और शैलेंद्र की अलग-अलग टीम बना दी थी—मुझे जयकिशन के साथ, शैलेंद्र को शंकर के साथ कर दिया था। वह मजाकिया भी कम नहीं थे। जय के साथ मेरी जोड़ी बनाकर मेरा नाम धर दिया था—'जय हसरतपुरी' फिर बाद में सुधार कर 'हसरत जयपुरी' कर दिया। शंकर के अक्खड़ स्वभाव तथा पहलवाननुमा सुडौल शरीर के कारण उनका नाम गैंडा महाराज रख दिया था। एक दिन हम लोग आरके स्टूडियो के म्यूजिक रूम में बैठे गप्पें हांक रहे थे कि तभी शंकर भी नियमानुसार आ पहुंचे। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में जाने कौन-सी शैतानी सूझी कि दो लाइनें लिख मारीं। राज की नजर पड़ी, तो उन्होंने लपक कर कागज मेरे हाथ से छीन लिया और जोर-जोर से पढ़ने लगे।

'गैंडे महाराज आये, हम लोगों के ताज आये
जैसे हमराज आये, गैंडे महाराज आये।'

फिर जोर से वाह-वाह करते हुए शंकर से बोले, "लो खूब लिखा इसने। अब तुम्हीं इसकी इन लाइनों पर धुन बना डालो। इसे मैं जब बच्चों के लिए फिल्म बनाऊंगा, तो उसमें उपयोग करूंगा।" एक दिन मुझसे बोले, "यार हसरत, तुम बहुत नामाकूल और खुश्क तबीयत के आदमी हो। अरे कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, किसी लड़की से प्रेम-व्रेम का चक्कर चलाओ, तभी तुम्हारा दिमाग चलेगा और प्रेरणा मिलेगी...अब शंकर, जय आदि को देखो। जब से इन लोगों ने चक्कर चलाया, तब से इनका दिमाग कितना चलने लगा है।..." फिर उसके बाद गाहे-बगाहे पूछने लगे, "क्या कोई चक्कर चला?"

एक दिन मैंने उन्हें खुशखबरी दी, साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड के नाम लिखी एक नज्म ***'ये मेरा प्रेम-पत्र पढ़कर, कि तुम नाराज मत होना...'*** सुनायी, तो वह अश-अश कर उठे और बोले, "देखा प्रेम का कमाल कि तुमने इतनी बेहतरीन नज्म लिख डाली। तुम्हारे इस नज्म को मैं अपनी फिल्म में उपयोग करूंगा।" वही नज्म गीत में ढल कर 'संगम' में सुपर हिट हुई थी।

रंगीन मिजाजी : वह शैतान और पुरमजाक भी कम नहीं थे। हम लोग चर्च गेट स्थित गेलार्ड रेस्तरां में बैठा करते थे, हमारी टेबुल एक तरह से रेस्तरांवालों ने रिजर्व कर रखी थी। रेस्तरां के पास ही एक कालेज था। जब लड़कियां सामने से गुजरतीं, तो राज और जय सीटियां बजाते और उन्हें कभी शोला, कभी बिजली या कभी कयामत की उपाधियां देते हुए फिकरे कसा करते थे। अपनी रंगीन मिजाजी में उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया था, "संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत भी आयी शबाब के बदले।"

वह इतने खुशमिजाज थे कि हमें बड़ी मुश्किल से उनके गुस्सैल चेहरे की याद आ पाती। एक बार 'जिस देश में गंगा बहती है' की कहानी सुनने के बाद शंकर ने कह दिया कि 'इसमें न तो गानों की गुंजाइश है और न ही इसकी सिचुएशनों पर गाने की धुन बन सकती है।' बस राज भड़क गये, "कैसे नहीं बन सकती है? इसमें वैसे ही गाने होंगे, जैसे मेरी दूसरी फिल्मों में हुआ करते हैं। अगर आप लोग नहीं बनायेंगे, तो मैं बनाऊंगा। राज कपूर की फिल्म बिना गाने के कैसे पूरी हो सकती है।" जयकिशन ने उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर शांत किया। दूसरे दिन जब हम लोग म्यूजिक रूम में पहुंचे, तो वह पहले से ही वहां मौजूद थे। हमारे पहुंचते ही उन्होंने कुछ धुनें सुनायीं, तो हम सभी उछल पड़े। वह धुन थी ***'ओ मैंने प्यार किया, हाय-हाय क्या ज़ुल्म किया'*** और ***'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना'*** तथा ***'हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने-सामने'***। ये तीनों गीत उन्होंने मुझसे ही लिखवाये।

बिखराव का दौर : नर्गिस के विवाह, फिर शैलेंद्र की मौत के बाद हमारी यूनिट में जो बिखराव शुरू हुआ, वह जयकिशन की मौत के बाद तो तुषारापात जैसा साबित हुआ। जयकिशन की याद कर राज कपूर अकसर रोने लगते। अगर जय की मौत नहीं हुई होती, तो शंकर जयकिशन की टीम हमेशा राज के साथ जुड़ी रहती। लेकिन वह एक अलग दास्तां है—तल्ख-भरी।

राज के लिए लिखी हसरत जयपुरी की ताजी नज्म

रास्ते प्यार के वीरान नजर आते हैं।
ये मेरे गीत परेशान नजर आते हैं॥
देखिये, देखिये, मांझी के चले जाने से।
अब किनारे हमें तूफान नजर आते हैं॥
हमसे अब कौन लिखायेगा रंगीले नगमे।
अपनी बरबादी के सामान नजर आते हैं॥
वे ही काटेज (राजजी का घर) जहां
सभी मिला करते थे।
उसके मंजर बड़े सूनसान नजर आते हैं।
आंन की आन में क्या हो गया देखो 'हसरत'।
बाग के फूल भी हैरान नजर आते हैं॥

राज की एक विशेषता थी—आदमी के भीतर के कलाकार को सेकेंडों में भांप कर उसकी गुणग्राहकता का आदर करना। एक बार वह अपने खास दोस्त टीपी झुनझुनवाला के घर दिल्ली उनसे मिलने गये, तो वहां पर संगीतकार रवींद्र जैन भी मौजूद थे। राज के पहुंचते ही वह बैठक संगीत महफिल में बदल गयीं। रवींद्र जैन ने अपनी एक रचना 'एक थी मीरा, एक थी राधा' उन्हें सुनायी, तो वह झूम उठे और जेब से रुपए निकाल कर उसी समय रवींद्र जैन को अनुबंधित कर लिया और हमेशा की तरह उनका भी नामकरण कर दिया—दादू! उसके बाद से राज और मैं रवींद्र जैन को 'दादू' कह कर पुकारने लगे। दादू तब से राज के साथ जुड़े रहे।

राज ने 'हिना' की पूरी तैयारी कर ली थी। मेरे लिखे गीतों को रवींद्र जैन ने लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकार्ड भी करा लिया था। नायक की भूमिका के लिए राजीव कपूर को चुन लिया था। अपनी मौत से एक महीना पहले उन्होंने हीरोइन का भी फैसला कर लिया था, लेकिन उसके नाम की घोषणा नहीं की थी। बीच में तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने पलंग पर पड़े-पड़े स्क्रिप्ट और डायलाग फाइनल कर लिये थे। संवाद के लिए फिल्म के संवाद वह पाकिस्तान के प्रख्यात लेखक हसीन मुईन के दो नाटक 'अनकही' एवं 'तनहाइयां' देखने के तुरंत बाद उनके पास जा पहुंचे और बोले, "मुईन भाई, आप लिखेंगे मेरी हिना के संवाद।"

अब इत्तिफाक था। मैं जब ज्यादा बीमार रहने लगा था, तो वह मुझे सांत्वना देने लगते, "हसरत, मेरी यूनिट के सारे साथी एक-एक कर दगा देकर चले गये। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दगा नहीं देने दूंगा। तुम्हें मरने नहीं दूंगा..."

मैं गीतों-नज्मों में कठिन शब्दों का उपयोग करता, तो वह बोलते, "म्यां इन्हें अपने दीवान (पुस्तक) के लिए रखो, फिल्मों में आसान गीत लिखा करो जो दर्शन के दिल में सीधे उतर जायें..." मेरा दीवान जब छपकर तैयार हो गया, तो मैंने उन्हें भेंट करने का निश्चय किया। दादा फालके पुरस्कार की घोषणा होने पर जब मैंने उन्हें बधाई दी, तो बोले, "इसमें तो तुम्हारा भी हिस्सा है। अब तुम्हीं तो मेरे एकमात्र हिस्सेदार बचे हो। दिल्ली से होकर आता हूं, तो जश्न मनायेंगे और तुम्हारे दीवान के नज्म भी सुनेंगे।" वह आये, चिरनिद्रा में सोये हुए। कागजी दीवान किसे भेंट करता मैं?

***"मैं अपनी तनहाई में कहां सिर फोड़ूं
मैं कहा जाऊं, क्या करूं
एक एक कर छोड़े सारे हम नशीं
और उनके गम उठाने को एक हमीं रह गये।"***

—प्रस्तुति : एस. राजेश

राज कपूर की स्त्रियां

अपनी अलबेली शख्सीयत से अनगिनत दिलों को आंदोलित करनेवाला बेजोड़ कलाकार राज कपूर अन्ततः २ जून, १९८८ की रात सांसों के संघर्ष में विदा-भूमिका अदा कर गये। बीमारी पहले की रही होगी, लेकिन उसका चरम-बिंदु इतना नाटकीय और आकस्मिक होगा, किसने सोचा था? उससे भी अद्भुत था राज कपूर का यह एक माह लंबा संघर्ष, जिसमें उन्होंने अपनी नीली आंखों से जीवन और मृत्यु-द्वार, दोनों अपने सामने बार-बार देखे होंगे। काश वह इस बीमारी से उबर पाते, तो हिंदी सिनेमा को अपने संघर्ष से सकेरा हुआ एक विलक्षण आयाम दे जाते। उनका मृत्यु-संघर्ष एक असंभव स्वप्न-दृश्य जैसा लगता रहा जो बार-बार उनकी फिल्मों में देखने को मिलता था। ताज्जुब यह है कि कहां तो मृत्यु बड़े-बड़ों के व्यक्तित्व को 'डि-मिस्टिफाइ' करती है, उनके रहस्य-आलोक को बुझाती है, लेकिन राज कपूर की मृत्यु ठीक उनकी फिल्मों की तरह उन्हें और भी मिस्टिफाइ कर गयी, रहस्य-आलोक को और भी गहरा कर गयी।

राज कपूर की फिल्में देखने पर कई किस्म की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने उनकी कौन-सी फिल्म पहले देखी। अगर आप 'बूट पॉलिश' देखें, तो आप कहेंगे राज कपूर एक यथार्थवादी कलाकार थे। अगर आप 'आवारा', 'श्री ४२०' देखें, तो आप उन्हें रूमानी या रोमांटिक यथार्थवादी कहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि राज कपूर की फिल्मों में अंकित स्त्रियों को देखकर आप एक ही प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे कि स्त्री के प्रति राज कपूर की दृष्टि नितांत सौंदर्यवादी, कलावादी थी, यथार्थवादी नहीं। उनकी हर फिल्म में नायिका का पहला शॉट उनके समूचे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। जीवन के सांध्यकाल में राज कपूर ने स्वीकार किया कि जिसे वह सौंदर्य समझ कर प्रस्तुत करते रहे, उसे दर्शकों ने कई बार मात्र उत्तेजना समझा। आश्चर्य है कि वह अपने पुरुष-पात्रों में यथार्थ और नारी-पात्रों में सौंदर्य प्रस्तुत करते रहे, इस नुस्खे का विलोम उन्होंने कभी प्रयोग के तौर पर नहीं किया। यही कारण है कि राज कपूर की नायिकाएं एक बेहद पर-निर्भर जीवन जीने को अभिशप्त हैं। वे बड़े स्तर की कोई लड़ाई नहीं लड़तीं, समय अथवा समाज से। उनकी समस्त लड़ाई अपने नायक से होती है, मीठी, भावुक झड़प। ये नायिकाएं मुख्यतः समर्पिताएं हैं। इस तरह की नारी-छवि इतनी लोकप्रिय इसलिए हुई, क्योंकि पुरुष प्रायः नारी का यही रूप प्रिय मानता आया है। राज-कपूर सही मायनो में नारी संबंधी सपनों के सौदागर थे।

पिछले दिनों राज कपूर को एक सजीव परपरा के रूप में दूरदर्शन पर एक विशेष कार्यक्रम में दिखाया गया। जैसे दूरदर्शन ने जन-जन की नब्ज पकड़ ली। अभिनेता राज ने औसत हिंदुस्तानी फटेहाल नवयुवक को परदे पर ऐसा चरितार्थ किया था कि एक विशाल युवा वर्ग का उनसे गहरा तादात्म्य हो गया। लड़के उनकी तरह चलने, बोलने, बाल रखने और कपड़े पहनने की कोशिश करने लगे। राज के व्यक्तित्व की एक और विशेषता, जिसने लोगों को प्रभावित किया, यह थी कि उनके पास खूबसूरत पत्नी के साथ-साथ एक खूबसूरत प्रेमिका भी थी। दोनों की अपनी-अपनी अलग जगह थी। दोनों में अगर कहीं कोई टकराव था भी, तो कभी जाहिर नहीं हुआ। दूरदर्शन कार्यक्रम में राज कपूर ने इस पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक उनकी पत्नी थी, उनके बच्चों की मां। दूसरी उनकी प्रेरणा थी; उनके काम की साथी।

बेमिसाल जोड़ी : नर्गिस और राज कपूर

एतराज इसी पर है। क्या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले अहम रिश्तों को इस तरह अलग-अलग महकमा सौंप सकता है? क्या पत्नी सिर्फ बच्चों की मां बनने के काबिल होती है? वह प्रेरणा नहीं बन सकती, प्रेयसी नही बन सकती? कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, समाज से यह छूट नहीं मांग सकता कि अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को अलग-अलग डिब्बे में बंद रखे। एक कलाकार की संवेदनशीलता यह गवारा नहीं कर सकती कि एक रिश्ते को वह केवल जिस्मानी और दूसरे को रूहानी रखे। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी प्रेमिका भी इस तरह के वर्ग-विभाजन को बरदाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों क्षेत्र बने ही एक दूसरे का अतिक्रमण करने के लिए हैं। यदि इन रिश्तों में अतिक्रमण नहीं होता, तो यकीनन उनमें कहीं कोई खोट है, कमी है, फासला है। 'पद्मावत' में जायसी ने सूफी मत के अंतर्गत भक्ति रचना के सारे मानदंड निभाते हुए भी इस द्वंद्व का अद्भुत चित्रण किया है।

प्रकारांतर से मैं सोचती हूं कि अगर कोई स्त्री-कलाकार इस तरह के मापदंड बना ले, तो समाज उसे कहां तक स्वीकार करेगा? कितनी ही स्त्रियां अपने-अपने कार्य या कला क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर हैं। अगर वे यह सोच लें और घोषित कर दें कि ठीक है यह घर में मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप और वह दूसरा मेरा प्रेरक है, मेरे काम का साथी, मेरा बॉस, मेरा मंत्री, मेरा सभापति। विचार मोहक, लेकिन खतरनाक है, समाज की शक्ल बिगाड़ने वाला। क्या पुरुष चुप रह कर ऐसे समानांतर संबंध स्वीकार कर लेगा? वह सबसे पहले दंड देने की सोचेगा। पहले वह पत्नी का सिर फोड़ेगा, फिर उसके प्रेरक का और अंत में शायद अपना। स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व ही जहां पुरुष को तकलीफ देने के लिए काफी है, वहां उसकी समानांतर नैतिकता तो कल्पना से परे की चीज होगी।

सवाल यह उठता है कि कलाकार को अपने लिए स्वीकृत सामाजिक ढांचे में कितनी छूट मिलनी चाहिए। भावना की गहराई, अभिव्यक्ति के विस्तार, प्रतिभा के आकलन जैसे बड़बोले दावों के बीच चुपके से अपने आचरण का डिस्काउंट कूपन समाज के काउंटर पर पेश करना, मेरे विचार से सरासर बेईमानी है। कलाकार एक मिसाल होता है, वह अपने आप में छवि और छवि का निर्माता, दोनों होता है। उसे चाहिए कि वह अपने आचरण और विचार में ऐसे सुविधाजनक मानक न बनायें जो बाद में उसी के लिए मारक सिद्ध हों।

—ममता कालिय

PRATIBHA ZARDA
प्रतिमा
PRABHAT ZARDA
PRABHAT
ZAFRANI PATTI
IS:2344
RATNA BRAND
ZAFRANI PATTI
रत्नाछाप
जाफरानी पत्ती
64
300
रत्नावली
जाफरानी पत्ती
सुगंधित चबाने की तम्बाकू पत्ती
रत्ना
पान मसाला
Jai
ZAFRANI PATTI
जय
जाफरानी पत्ती
PRIYA
ZAFRANI PATTI
किवाम
TRADE MARK
REGD. NO. 296632
दमकते प्रभात के
चमकते सितारे
प्रभात ज़र्दा उत्पादन
वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

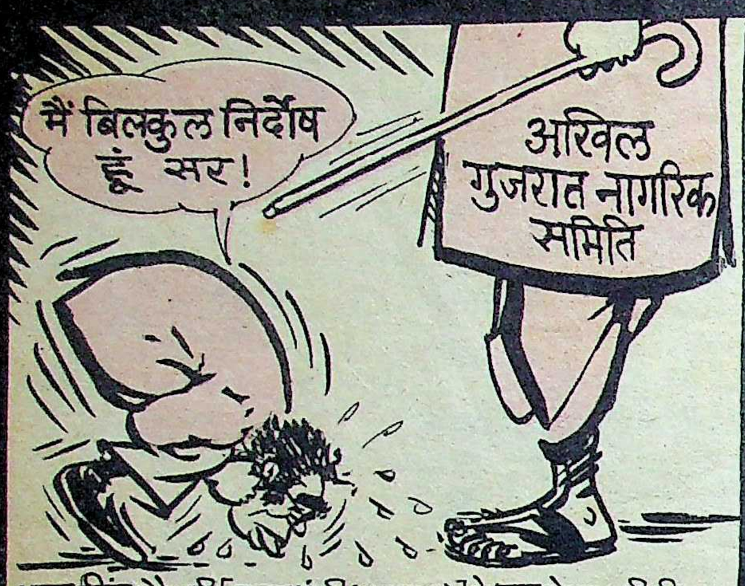
मैं बिलकुल निर्दोष हूं सर!
अखिल गुजरात नागरिक समिति

अमरसिंह चौधरी [मुख्यमंत्री (गुजरात)] के पुत्र को एम.बी.बी.एस. (द्वितीय वर्ष) में पास के लिए अनुग्रहांक दिये जाने से हंगामा —

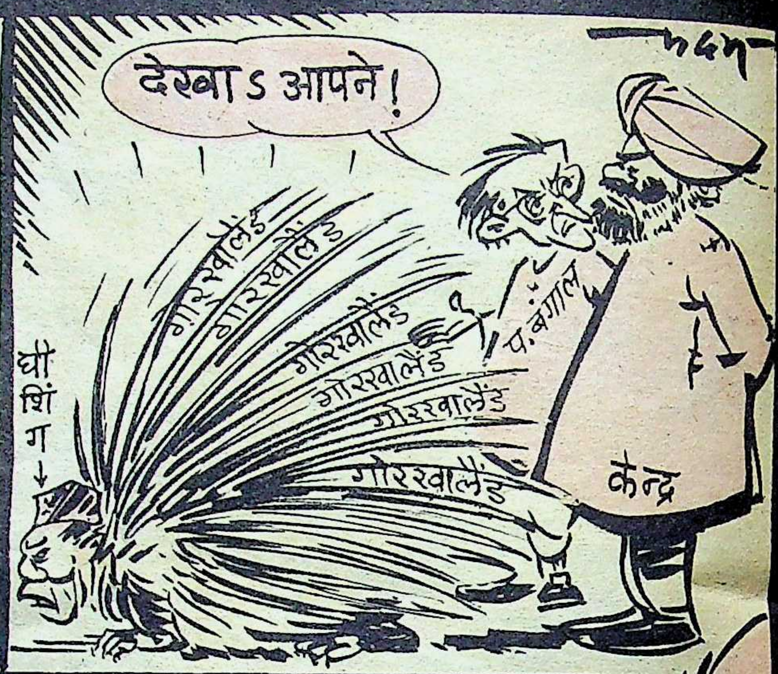
देखा ऽ आपने!
गोरखालैंड
गोरखालैंड
गोरखालैंड
गोरखालैंड
गोरखालैंड
गोरखालैंड
घीशिंग
प. बंगाल
केन्द्र

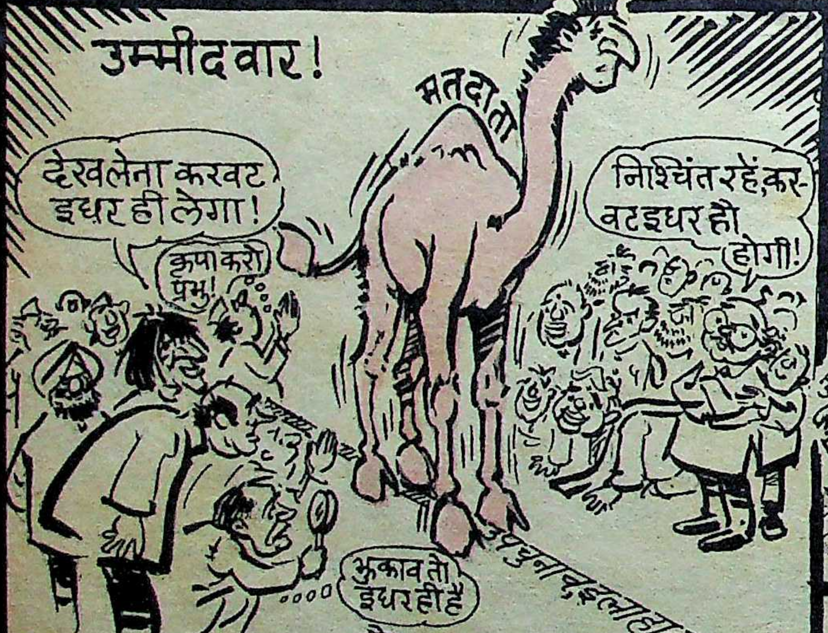
उम्मीदवार!
मतदाता
देखलेना करवट इधर ही लेगा!
कृपा करो प्रभु!
निश्चिंत रहें, करवट इधर ही होगी!
झुकाव तो इधर ही है

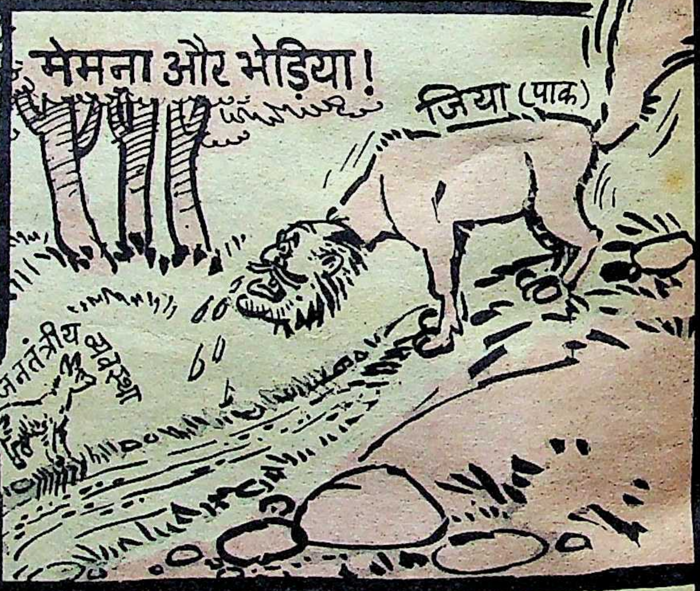
मेमना और भेड़िया!
जिया (पाक)
जनतंत्रीय व्यवस्था

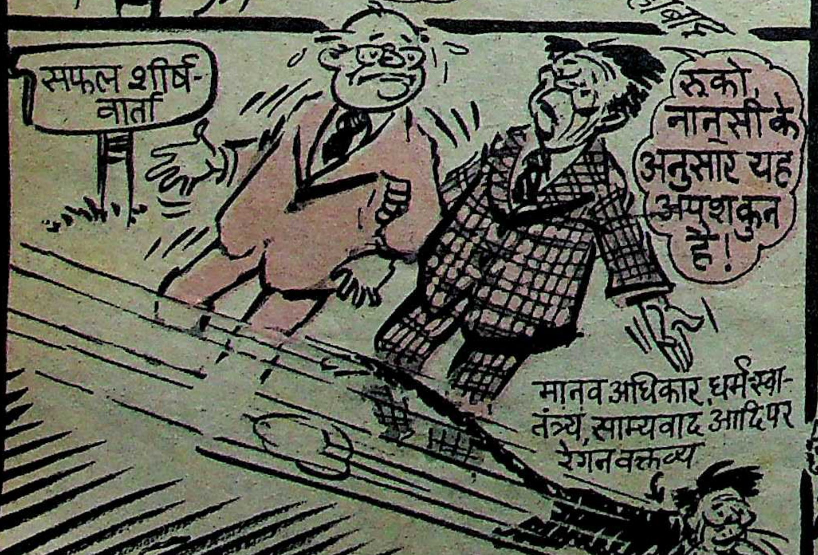
सफल शीर्ष-वार्ता
रुको, नानसी के अनुसार यह अपशकुन है!
मानव अधिकार, धर्मस्वातंत्र्य, साम्यवाद आदि पर रेगन वक्तव्य

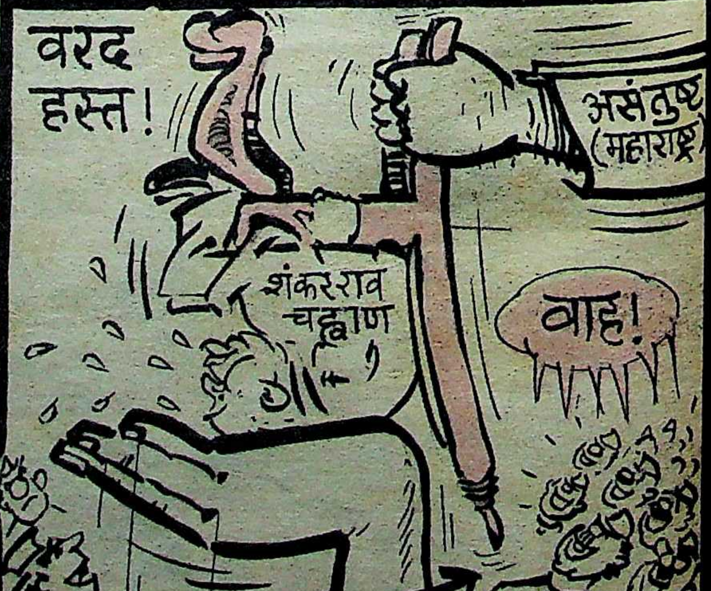
वरद हस्त!
असंतुष्ट (महाराष्ट्र)
शंकरराव चह्वाण
वाह!
श्रेष्ठीवर्ग

मौत के बाद शादी

लड़के-लड़की की शादी होना, तो कोई खास बात नहीं, लेकिन यदि दो पुतलों की शादी और वह भी धूमधाम से हो, तो दांतों तले उंगली तो दबानी ही पड़ती है, लेकिन मलेशिया के पिनांग में ऐसी ही एक घटना घटी। शादी कराने की पहल दूल्हे (मृतक लिम हांग जुआट) की मां ने की। उसने बताया कि स्वप्न में उसके लड़के जुआट ने अपनी शादी की बात उससे कही। उसकी मां ने लड़की वालों से बातचीत की। दोनों के पुतले बनवाये गये और शादी की तारीख मुकर्रर की गयी। यह शादी अत्यंत धूमधाम से एक मंदिर में हुई, जिसमें सौ-सवा सौ लोग इकट्ठे हुए। वधू-पक्ष ने वर-पक्ष को दहेज के रूप में कार, टीवी, वीडियो रिकार्डर, सोफे पलंग आलमारी आदि भी दिये।

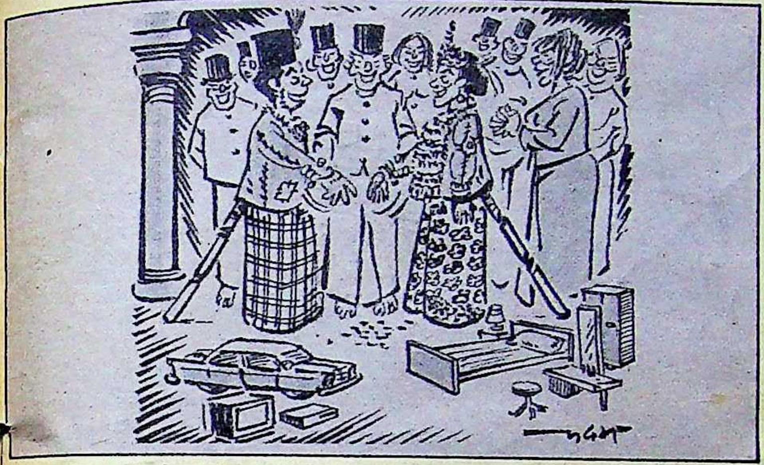

दरअसल आज से १५ वर्ष पूर्व २५ वर्षीय लिम हांग जुआट की मृत्यु कैंसर से तथा उसकी होनेवाली १२ वर्षीय पत्नी सा वी हांग की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गयी थी। दोनों की असामयिक मृत्यु के कारण उस समय उनकी शादी न हो सकी थी। लेकिन जुआट की आत्मा शादी के लिए भटकती रही। अंततः उसकी मां ने उसकी इच्छा १५ साल बाद पूरी कर ही दी।

चुटकुलेबाज

इस दुनिया में एक-से-एक लोग पड़े हैं। अब बेलग्रेड के मिरोस्लैव मिहैलोविक को ही ले लीजिए। इन्होंने ५५ घंटे तक चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाने का रिकार्ड ही कायम कर दिया है। तारीफ की बात तो यह कि एक भी चुटकुला वह दुहराते नहीं, सभी चुटकुले नये ईजाद करते हैं। चुटकुले बनाना और लोगों को हंसाते रहना, उनके लिए बायें हाथ का खेल है। मिरोस्लैव का दावा है कि उन्हें तकरीबन २ लाख ८७ हजार चुटकुले याद हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उन्हें ५० लाख तक करना है। मिरोस्लैव का कहना है कि 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स' के संपादक ने उनके लिए एक मोटी फाइल भी खोल रखी है, लेकिन उनका नाम रिकार्ड में तभी दर्ज होगा, जब वह चुटकुला सुनाने की मैराथन में सफल हो जायेंगे। मिरोस्लैव का कहना है कि वह मृत्यु शैया पर पड़े आदमी को भी हंसा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं पैदा हुआ है, जो उन्हें हंसा सके। बहरहाल, दुनिया भर में उनकी गिनती हंसी के बेताज बादशाह के रूप में होती है।

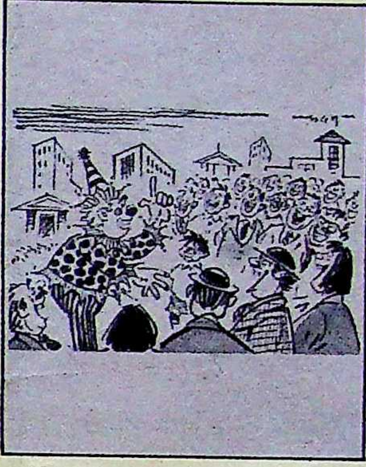

बिल्लियों के नाम वसीयत

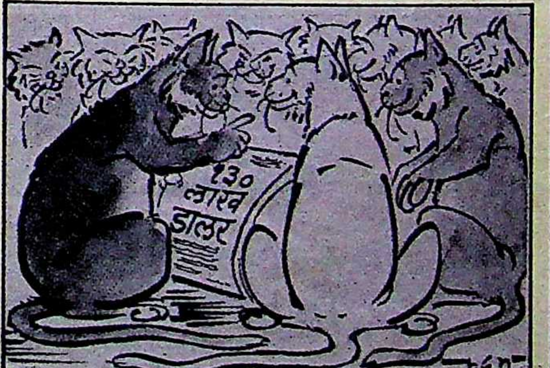

मरने के बाद कुछ लोग अपनी जमीन-जायदाद अपने रिश्तेदारों-नातेदारों को दे जाते हैं, तो कुछ लोग संस्थाओं आदि के नाम लिख जाते हैं, लेकिन लंदन के ८२ वर्षीय बिल्ली प्रेमी बेन री जब मरे, तो उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी १३० लाख डालर की संपत्ति बिल्लियों के नाम लिख दी। जब बेन री की वसीयत पढ़ी जा रही थी, तो उनके रिश्तेदार बड़ी शांति से कान लगाये बैठे थे कि शायद उनके नाम भी कुछ छोड़ गये हों, लेकिन वसीयत में अपना नाम न आने पर उन लोगों ने बेन री को जी भरकर कोसा। मजे की बात तो यह है कि बेन री ने अपना पूरा जीवन बड़ी कंजूसी में गुजारा, पुराने-धुराने कपड़े पहने, लेकिन इतिहास की दुर्लभ कलाकृतियों के विक्रेता होने के कारण उसने लाखों डालर कमाये। पता नहीं क्या जानकर उसने अपने माली, नलसाज, कार मिस्त्री और एकाउंटेंट के नाम कुछ डालर छोड़ दिये।

दो जिस्म एक जान

आम तौर पर समझा जाता है कि जितना जागरूक मनुष्य है तथा प्रेम की जो प्रगाढ़ता एक स्त्री-पुरुष में होती है, न तो उतनी जागरूकता जानवरों में होती होगी और न उनमें उतनी प्रेम विह्वलता। लेकिन कभी-कभी ऐसी मार्मिक घटनाएं हो जाती हैं कि हतप्रभ हुए बिना नहीं रहा जा सकता।

अफ्रीका के साराजेवो में जेब्रा (जानवरों) के एक जोड़े ने अपनी स्वतंत्रता छिन जाने तथा आपसी जुदाई के कारण आत्महत्या कर ली। हुआ यों कि ये जेब्रा युगल एक चिड़िया घर में साथ-साथ रहते थे और स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते थे, लेकिन चिड़िया घर के अधिकारियों ने उन्हें एक नये, किंतु छोटे पिंजड़े में रखने की योजना बनायी। लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी स्वतंत्रता में खलल डालने के लिए उन्हें नयी जगह दी जा रही है। दोनों ने मानो नये पिंजड़े में न जाने की कसम खा ली थी। चिड़ियाघर के चौकीदार बड़े परेशान हुए, लेकिन किसी तरह भी वे उनको नये पिंजड़े में न ले जा सके। अंततः उन्होंने खाने के साथ उन्हें नशीली दवाएं दीं। जब दोनों बिलकुल पस्त होकर गिर गये, तब सबसे पहले मादा जेब्रा को नयें पिंजड़े में ले जाया गया। पिंजड़े में ले जाने के कुछ ही देर बाद उस मादा जेब्रा ने फर्श पर अपना सिर मार-मारकर अपने प्राण त्याग दिये। अपनी प्रेमिका के गम में नर जेब्रा इतना बेचैन हुआ कि उसने अपना संतुलन तक खो दिया। जब चिड़ियाघर के अधिकारियों से उसकी बेचैनी नहीं देखी गयी, तो अतंत उन्हें उसे गोली ही मारनी पड़ी। इनकी विरह-व्यथा पर काश कोई महाकाव्य लिख पाता।

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

स्वामीजी की सनक

इस दशक की भव्यतम फिल्म 'बंटवारा' की ११० दिनों की निरंतर शूटिंग कर स्वामी विनोदानंद उर्फ गन-मैन विनोद खन्ना जब से बंबई लौटे हैं, तब से उन्हें ३५ एमएम का लेंस, अपनी विशाल शख्सीयत के सामने बौना-सा लगने लगा है। उन्होंने अपने फिल्म निर्माताओं को हुक्म दे दिया है कि वे अगर ७० एमएम की फिल्मों की शूटिंग करेंगे, तभी वह उनकी फिल्मों में काम करेंगे। उनकी इस ७० एमएम सनक ने बेचारे उन फिल्म निर्माताओं को परेशानी में डाल दिया है, जिन्होंने २० से ३५ प्रतिशत ब्याज पर फाइनेंसरों से कर्ज लेकर फिल्म की कई रीलें बना डाली हैं। बेचारे एक फिल्म निर्माता को तो यह फरमान सुनते ही स्वामीजी के वातानुकूलित मेकअप रूम में गश-सा आ गया।

निर्माता के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि अभी तक शूट की गयी छह रीलों को कचरे की टोकरी में डालकर ४० लाख रुपए का नुकसान उठाकर नये सिरे से शूटिंग की जाये। लेकिन लता मंगेशकर की फिल्म 'लेकिन' के निर्देशक गुलजार ने स्वामीजी की बात मानने से इनकार कर दिया कि अगर ७० एमएम के डीलडौल वाले अमजद खान ३५ एमएम की रील में समा सकते हैं, तो ८ एमएम की हुलियावाले स्वामीजी क्यों नहीं?

स्वामी गन-मैन के इस हुक्मनामे का खासा फायदा बेरोजगार हो रहे उनके एक दोस्त को मिला तथा ७० एमएम के लेंस वाले कैमरों की जो खेप गोदाम में पड़ी जंग खा रही थी, अब उसकी पूछ कुछ इतनी अधिक बढ़ गयी कि फिल्म निर्माता पहले कैमरे की डेट्स लेते हैं, फिर हीरो-हीरोइनों को साइन करते हैं।

जयाप्रदा का दिव्य ज्ञान

अपनी कद-काठी और चेहरे-मोहरे से, खूबसूरती के बावजूद, ग्लैमर के मामले में श्रीदेवी से मार खा जानेवाली जयाप्रदा जब से हालीवुड का सफर करके लौटी हैं, तब से उनकी हुलिया-तो-हुलिया, तौर-तरीका भी बदल गया है। अब फिल्मी पार्टियों में श्रीदेवी जहां साड़ी में सजी-बजी कदमबोसी करती हैं और नीबू-पानी के गिलास से ही काम चला लेती हैं, वहीं जयाप्रदा हालीवुड और पेरिस के बाजारों से खरीद कर लाये माड परिधानों में शिरकत करती हैं और बेयरे से कभी कंपारी, तो कभी ऐसी शराब का नाम लेती हैं, जिसका नाम भी उसने नहीं सुना होता है।

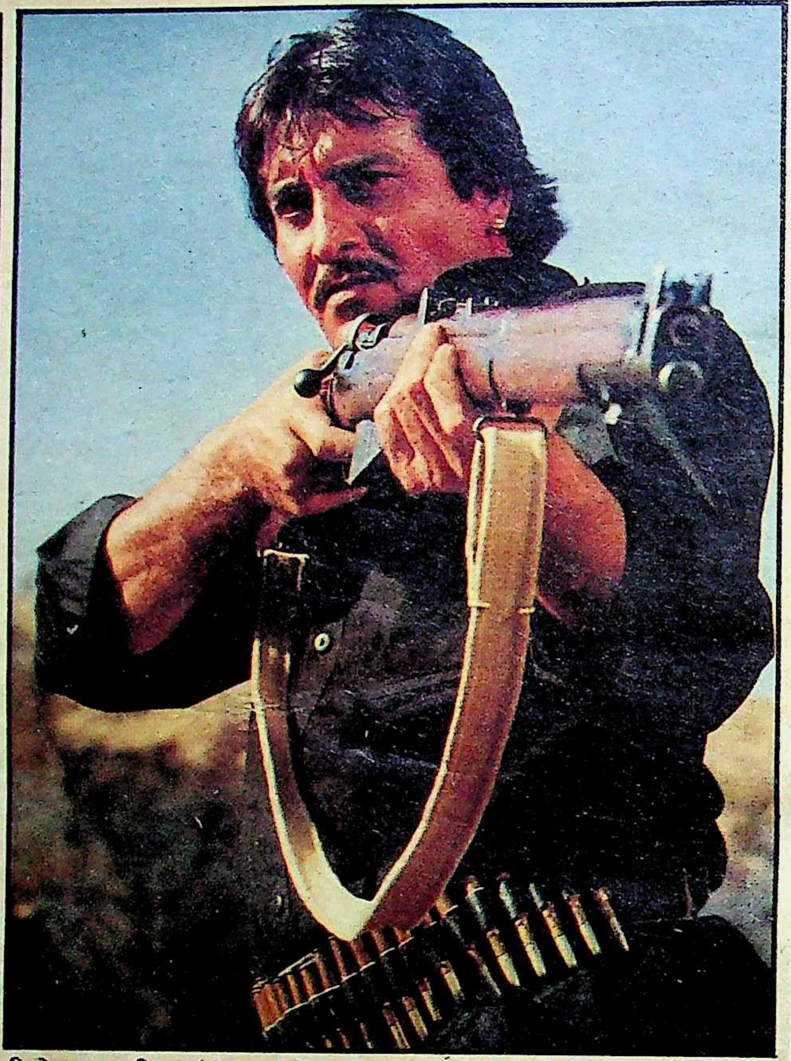

विनोद खन्ना फिल्म 'बंटवारा' में

हालीवुडी स्टारों से मिलने की तमन्ना में उन्हें जो-जो पापड़ बेलने पड़े, उसने उन्हें एक नया दिव्य ज्ञान दिया और बंबई आते ही उन्होंने उस पर अमल भी शुरू कर दिया। हालीवुडी सितारों के अगर इंटरव्यू लेने हों, तो आपको पूरी प्रश्नावली उनके प्रेस एजेंट को थमानी पड़ती है, साथ ही चित्रों के लिए उन पोजों का वर्णन भी, जिस तरह के छापने हों। अब जयाप्रदा ने भी साक्षात्कार चाहनेवाले पत्रकारों को निर्देश देना शुरू कर दिया है कि 'आप अपनी प्रश्नावली मेरे पीआरओ को दे दीजिए, एक सप्ताह बाद वह आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दे देगा। मैं सारे सवालों के जवाब उसे 'डिक्टेट' करा दूंगी।' एक खिसियाये पत्रकार ने जयाप्रदा से तुर्की-ब-तुर्की यह सवाल कर कि आपका पीआरओ और आप 'डिक्टेट' की स्पेलिंग जानती हैं? वहां से तुरंत खिसक लिया। जयाप्रदा स्पेलिंग शायद जानती थीं, उन्होंने अपनी हेयर ड्रेसर से कहा, "तुरंत पीआरओ को बुलाओ और कह दो कि इस शख्स को यहां कभी न घुसने दे..."

पत्रकारों के नाम से भी परहेज करने वाली रेखा को जयाप्रदा के नये दिव्य ज्ञान से फायदा उठाना चाहिए।

मावदौलत की किरकिरी!

अपने से सिर्फ दो वर्ष बड़ी नर्गिस से जब सुनील दत्त ने विवाह किया था, तो समूची फिल्म इंडस्ट्री में जैसे सैलाब-सा आ गया था, लेकिन अपने से १० वर्ष बड़ी जरीना वहाब से

जयाप्रदा छाया : तैयब बादशाह

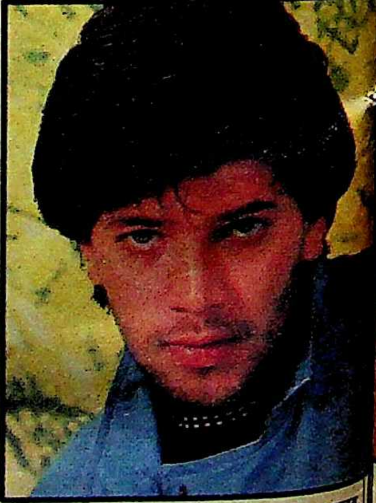

आदित्य पंचोली छाया : डीबार यादव

विवाह करनेवाले आदित्य पंचोली की जिंदगी में सैलाब तब आया, जब उन्होंने केसी बोकाड़िया की फिल्म 'कब तक चुप रहूंगी' के बाद निर्माता सलीम की फिल्म 'कातिल' साइन की। 'कब तक चुप रहूंगी' की असफलता के कारण आदित्य की डूबती नैया को 'कातिल' ने बचा तो लिया, लेकिन उनके स्टारपने को कुछ

इस कदर सिर चढ़ा दिया कि जिन निर्माताओं के घर कभी आदित्य चक्कर लगाते नहीं थकते थे, अब उन्हीं से अपने घर का चक्कर लगवाते नहीं थकते। ऐसे में थके-हारे एक फिल्म निर्माता ने आदित्य के नखरों से तंग आकर उनकी जगह गोंविदा को ले लिया, दूसरे ने चंकी पांडे को और तीसरे ने अपनी फिल्म ही डिब्बे में बंद कर काशी की बजाय जुहू में डुबकी लगाकर फिल्म निर्माण से ही तौबा कर ली। लेकिन एक फिल्म निर्माता सेर का सवा सेर निकला।

ऊटी में शूटिंग करते-करते आदित्य को एक दिन खुद के सुपर स्टार होने का जो भ्रम हुआ, तो उसने प्रोडक्शन के आदमी को बुलाकर राज कुमार के हीरोआना अंदाज में हुक्म फरमाया कि उनके लिए तुरंत बंबई का हवाई जहाज मुहैया कराया जाये, माबदौलत को बेगम साहिबा की याद सता रही है। डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन सहायक तक ने माबदौलत को बहुत समझाया, लेकिन बेगम साहिबा की याद में पगलाये माबदौलत किसी भी शर्त पर रुकने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिल्म निर्माता ने निर्देश दिया, "ठीक है उन्हें टिकट भी दे दो और फिल्म बंदी की नोटिस भी। हमें नहीं बनानी उस नामाकूल के साथ फिल्म।"

बेचारे माबदौलत का नशा ऐसा हिरन हुआ कि अगले एक पखवारे तक उन्हें बेगम साहिबा सपने तक में नहीं याद आयीं।

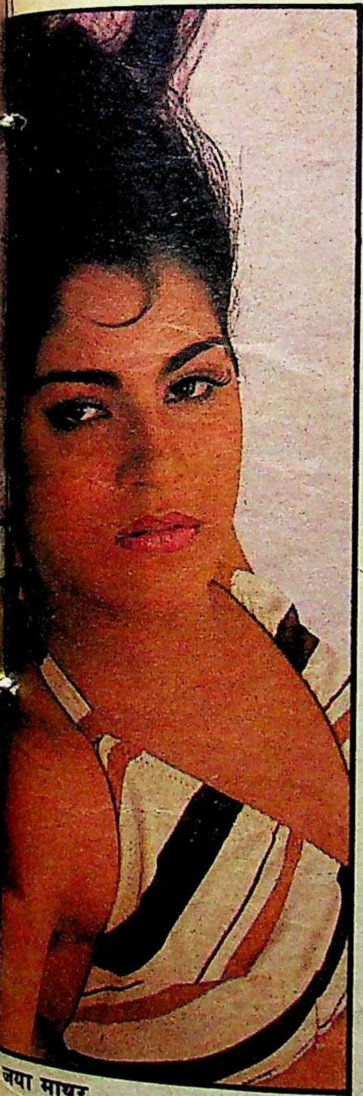

जया माथुर

छाया: तैयब बादशाह

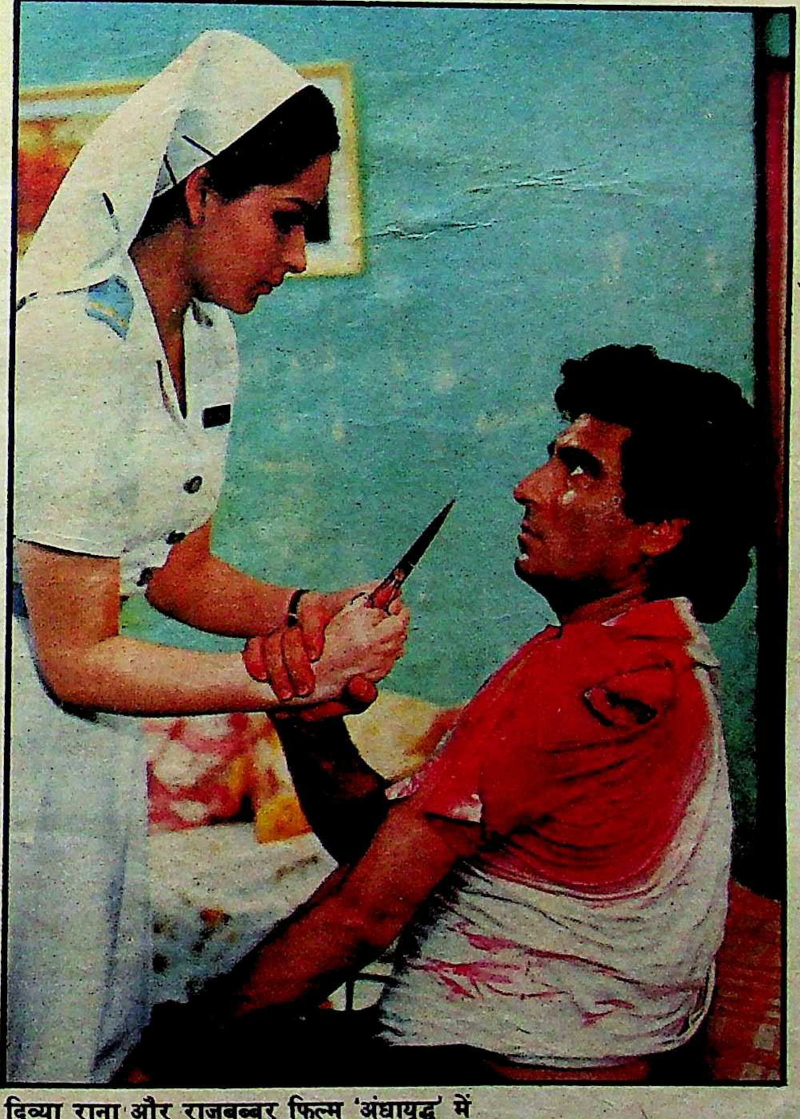

दिव्या राना और राजबब्बर फिल्म 'अंधायुद्ध' में

जया का नशा

फिल्म इंडस्ट्री में 'जया' शब्द का कुछ नशा ही ऐसा है कि बड़े-तो-बड़े छोटे भी बौरा जाते हैं। एक जमाने में जया भादुड़ी कुछ इस कदर चमकीं कि बंबई से लेकर मद्रास तक की दर्जनों अभिनेत्रियों ने अपना अच्छा भला नाम बदल कर ऐरे-गैरे तखल्लुसों के साथ 'जया' शब्द जोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया कि वह जया भादुड़ी के फिल्मों से संन्यास ले लेने के सवा दशक बाद तक जारी है।

चार-चार पीढ़ी के कलाकारों से अपनी शर्त पर काम लेनेवाले निर्माता-निर्देशक मोहन कुमार को उस समय जैसे पसीने छूट गये, जब उनकी फिल्म 'अंबा' में काम कर रही नवोदित जया माथुर ने अपने नखरों से यूनिट की नाक में दम कर दिया, "उसे वातानुकूलित मेकअप रूम चाहिए, उसका लंच पंचसितारा होटल से आना चाहिए, उसे आने-जाने के लिए प्रोडक्शन की कार मुहैया की जानी चाहिए, आदि-आदि..." अब मोहन कुमार ठहरे मोहन कुमार, जिनसे वैजयंती माला व राजेंद्र कुमार अपने सुपरस्टारी के दिनों में थरति थे और हेमामालिनी, राजेश खन्ना तथा शबाना आजमी भी नखरा करने से घबड़ाते थे। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया कि वह मैडम को समझा दे या बोरिया-बिस्तर उठाकर घर जाने के लिए कार में बिठा दे।

सेक्स, खूबसूरती और ग्लैमर में श्रीदेवी से लेकर रेखा तक की नाक काटने का दम भरने वाली जया माथुर ने तब क्या किया, पता नहीं, लेकिन वह इस घटना को बेसिर-पैर की उड़ायी अफवाह जरूर मानती है कि वह तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में वह इस तरह की हिमाकत भला कैसे कर सकती है?

लेकिन उस हादसे का वर्णन जो 'अंबा' की यूनिट वाले करते हैं, उसके लिए क्या कहेगी जया?

निहलानियों का आतंक

गोविंद निहलानी की 'तमस' विवाद और सुर्खियों का विषय क्या बनी कि इंडस्ट्री में निहलानियों के नाम का डंका-सा बजने लगा। गोविंद ने कई फिल्में बनायीं, लेकिन 'विजेता' और 'अर्द्धसत्य' को छोड़कर कोई भी फिल्म खरीदार के अभाव में सिनेमाघर का मुंह नहीं देख सकी। फलतः गोविंद को अपनी फिल्में उस दूरदर्शन के हवाले करनी पड़ीं, जिसे कभी वह फिल्में देने की बजाय डिब्बे में बंद रखना ज्यादा पसंद करते थे।

उसी गोविंद के छोटे भाई दयाल निहलानी ने पंजाब में आतंकवाद को लेकर एक फिल्म बनायी है— 'अंधा युद्ध', जबकि दूसरे फिल्मकार इस विषय को इसलिए छूने से कतराते रहे कि कहीं आतंकवादियों की कृपादृष्टि उन पर न पड़ जाये। आतंकवादियों की बंदूक से भी धारदार आवाज में बरसनेवाले राज बब्बर 'अंधा युद्ध' के नायक हैं।

निहलानी बंधुओं के अलावा एक और निहलानी—पहलाज निहलानी की काबिलीयत के झंडे आजकल बुलंदियों पर फहराने लगे हैं। उनके बारे में एक कहावत है कि वह मिट्टी (नये लड़के-लड़कियों) पर भी हाथ रख दें, तो सोना (स्टार) बन जाता है। गोविंदा, चंकी पांडे, सुमीत सहगल, नीलम तथा फरहा को स्टार बनाने के बाद वह अब सन्नी देवल, जैकी श्राफ और मंदाकिनी की डूबती नैया संवारने में लगे हैं।

—अखबारी लाल

अब्दुल सत्तार

संबंधों की निकटता के लिए बढ़े हाथ

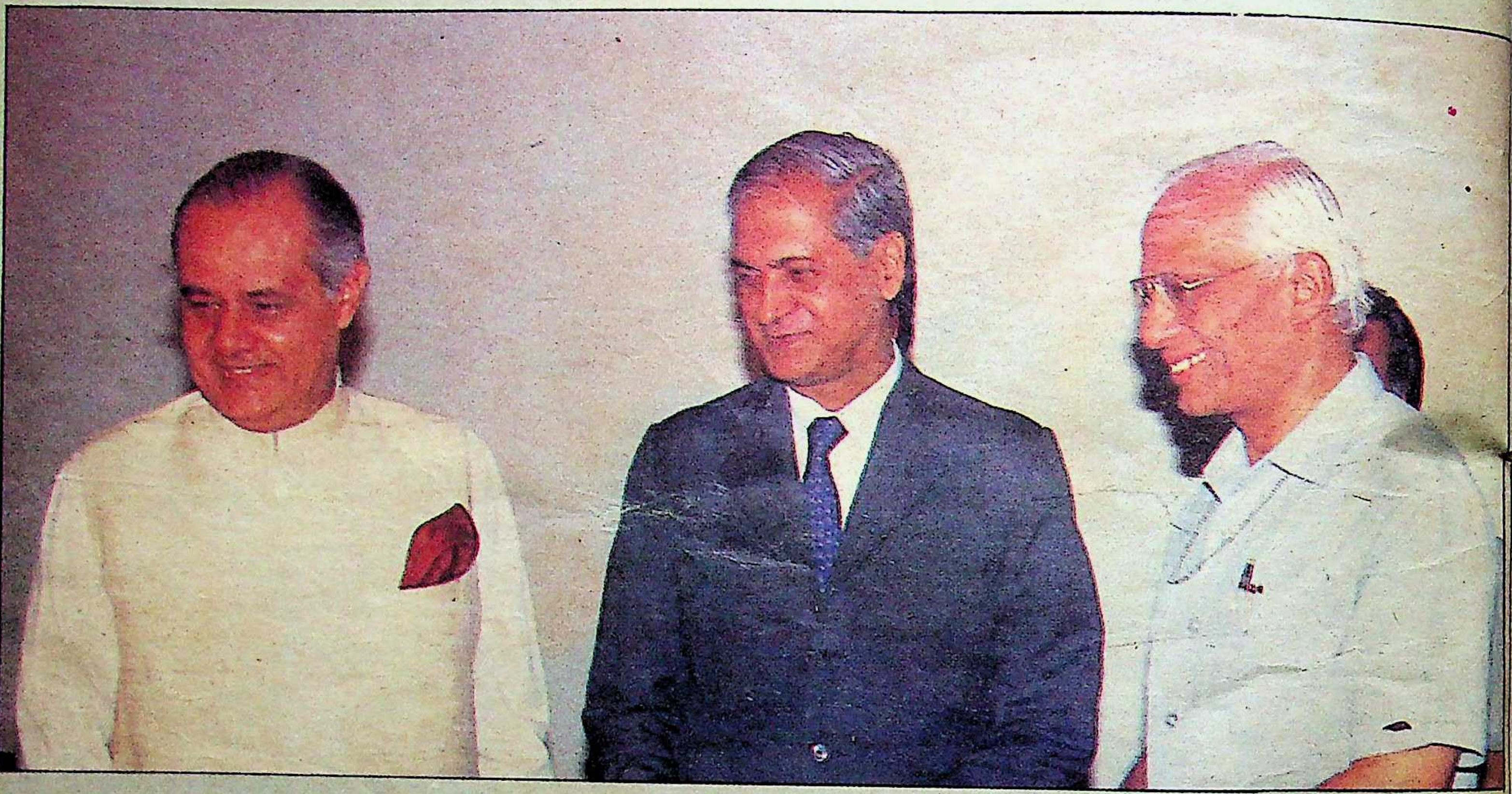

भारत और पाकिस्तान दोनों के आपसी संबंधों में जहां अनेक मुद्दों को लेकर संदेह की गुंजाइश बनी रहती है, वहां दोनों ही देशों के उच्च अधिकारियों का मिलना-जुलना एक नयी उम्मीद पैदा कर देता है। ऐसे ही खट्टे-मीठे मसलों को जन्म देने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव अब्दुल सत्तार का मई महीने की ३१वीं तारीख को भारत आगमन हुआ और यह उम्मीद बंधी कि आपसी बातचीत से दोनों पड़ोसियों के बीच, जो संदेह की एक धुंध बनी हुई थी, वह कटेगी।

अब्दुल सत्तार का आगमन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि पाकिस्तान द्वारा जो 'अयुद्ध संधि' का प्रस्ताव उसकी ओर से आया था, उस पर कुछ अमल हो सकेगा। दरअसल, पाकिस्तान भारत के सामने यह प्रस्ताव रखता आया है कि हम दोनों आपस में कभी कोई युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन, दूसरी ओर भारत यह चाहता रहा है कि 'अयुद्ध संधि' की जगह पाकिस्तान एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करे, जो दोनों देशों में शांति, सहयोग और मैत्री को बढ़ावा दे। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत किसी ऐसी संधि में नहीं बंधना चाहता था कि उसे भविष्य में बदली हुई किसी परिस्थिति में पंगु होना पडे। इसलिए यह मामला टलता रहा। वैसे भी जब दोनों में आपसी खुलूस का अभाव है, तब इस प्रकार की बड़ी-बड़ी बातें बालू में नाव चलाने के अलावा और क्या हो सकतीं थीं। शायद यही कारण है कि जब भारत ने पाकिस्तान के सम्मुख यह मुद्दा रखा कि वह अपने देश में दूसरे देशों का सैनिक अड्डा न बनने दे, तो इस पर पाकिस्तान का दो टूक जवाब था कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है कि अपने देश में वह क्या करता है, इससे भारत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए।

यह सही है कि दोनों देशों के गृह सचिवों और रक्षा सचिवों की विभिन्न मसलों पर बातें हुईं, जिनमें एक ओर सीमाओं पर संयुक्त रूप से सुरक्षात्मक टुकड़ियां लगाने की बातें रखी गयीं, तो दूसरी ओर सियाचिन का मामला उठे बिना नहीं रह सका। लेकिन इन मसलों में भी कुछ-न-कुछ पेंच निकालकर उनको वहीं छोड़ दिया गया, जहां से वे उठे थे। सियाचिन के मामले में इस्लामाबाद में यह तय हुआ था कि सियाचिन के कुछ भाग को निर्जन क्षेत्र (नो मैंस लैंड) घोषित कर दिया जायेगा, जिस पर किसी का अधिकार नहीं माना जायेगा, लेकिन भारत इस बात पर अड़ गया कि जब एक लंबे अरसे से वह उस पर काबिज़ है और उसकों पाने के लिए उसने जद्दोजहद की है, तब यह कैसे संभव है कि वह उसे हाथ से ऐसे ही खिसक जाने दे। पाकिस्तान चाहता था कि शिमला समझौते को मद्देनजर रखते हुए भारत को चाहिए कि वह अपनी सेनाएं वापस कर ले, लेकिन यह भी मामला खटाई में ही पड़ गया।

बीच-बीच में फुलझड़ी छोड़नेवालों की भी कमी नहीं रही है, जिसके चलतें दोनों के आपसी संबंधों में और खट्टापन बढ़ता गया है। काफी दिनों से भाई चारे की बातों के प्रयास चल ही रहे थे कि किसी ने यह उड़ा दिया कि पाकिस्तान ने एक ऐसे असाधारण प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है जिसकी चपेट में दिल्ली और बंबई तक आ जायेंगे। इस प्रचार की अफवाहों से बिगड़ते संबंध क्या बनते संबंधों पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं। बहरहाल, दोनों के संबंधों में दरार लाने की जिम्मेदारी इन मसलों के अलावा पाकिस्तान द्वारा सिख उग्रवादियों को अपने यहां कथित ट्रेनिंग और शरण देने तथा अफगान के मामले पर पाकिस्तान के रुख पर भी बहुत कुछ है।

कहना न होगा कि इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत पधारे। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस कोशिश को दोनों देशों के सचिवों के राजनीतिक साहस और दृढ़ निश्चय की संज्ञा दी जा सकती है।

—डा० मुश्ताक अली

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

15/7/88
पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

DUPLICATE

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

''मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।''

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंशः

''सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढिया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।''

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's®

दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMH/V-4

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मज़ेदार भोजन के नए ढंग
सूर्य सेवियों के संग!

सूर्य सेवियों से बने नये व्यंजन हर दिन आपके परिवार को लज़ीज़ खाने का आनन्द देते हैं।
सूर्य सेवियाँ व्यंजनों की नई विधियों का अन्त नहीं, सेवियाँ कटलेट, सेवियाँ कोफ़्ता, सेवियाँ मुर्ग....भारतीय रसोई में भी सूर्य सेवियों ने अपनी जगह बना ली है। सूर्य सेवियों की खीर और हलवा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है।

सूर्य सेवियाँ —
खाने की कलात्मक शुरूआत

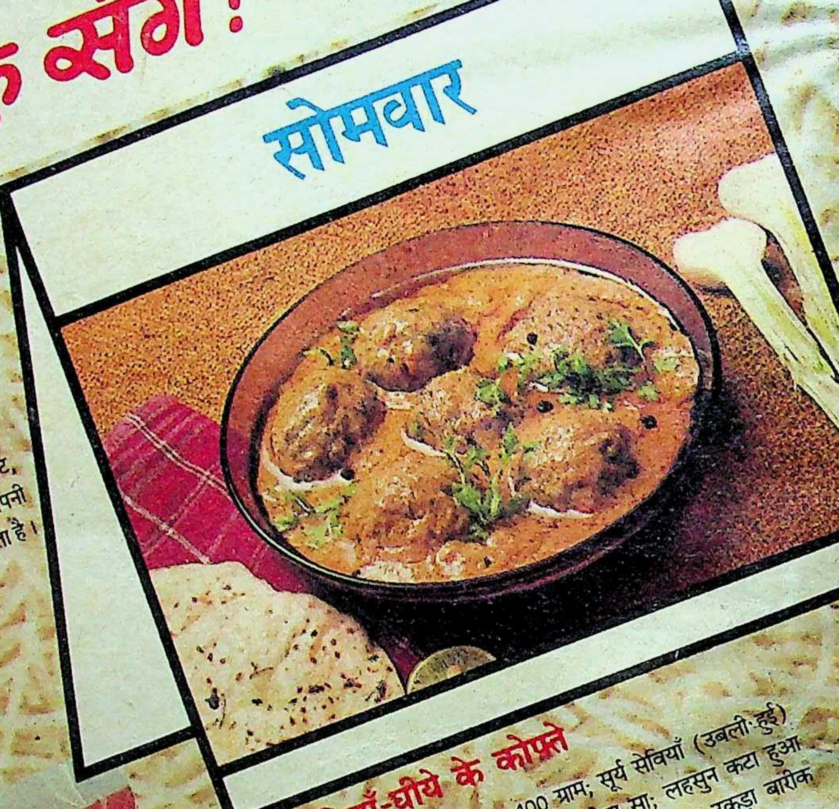

सूर्य सेवियाँ-घीये के कोफ़्ते

सामग्री : कसा और उबला घीया 400 ग्राम; सूर्य सेवियाँ (उबली हुई) 150 ग्राम; हरा धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा; लहसुन कटा हुआ 8 तुरी; हरी मिर्च बारीक कटी हुई 4; अदरक का छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ; बेसन 100 ग्राम; तेल अंदाज़ से तलने के लिए; दूध 2 कप।

तरी के लिए : टमाटर आधा कि., प्याज़ 4 बड़े; धनिया; हल्दी; नमक; तेल 1 कप।

विधि : घीया, सेवियाँ, हरा धनिया, हरी मिर्च और दूध भगौने में चढ़ाकर 5 मिनट तक पकाएं। जब घीया और सेवियाँ घुट जाएं तो आँच से उतारकर इसमें बेसन मिला दें। ठंडा हो जाने पर इसके कोफ़्ते बना कर फ्रिज में 20 मिनट रख दें। फ्रिज से निकालकर कोफ़्ते खुले तेल में सुर्ख कर लें।

तरी : घी/तेल गर्म करें और प्याज़ को भून लें। इसमें नमक, हल्दी, बारीक अदरक और टमाटर का रस मिला कर पका लें (जब तक घी ऊपर आ जाए)। थोड़ा पानी डालकर फिर पकाएं जब तक मसालों की कचाँद न निकल जाए। इसमें सूर्य सेवियों के बने कोफ़्ते डालकर हल्के हाथ से चलाएं। तैयार होने पर कटे टमाटर और हरे धनिये से सजाएं।

SURYA'S
VERMICELLI
सूर्य सेवियाँ

जल्दी कीजिए! साथ लगे कूपन को भरकर भेजिए और शीघ्र अपनी सूर्य सेवियाँ पाक-विधि पुस्तिका पाइये।

हाँ! मुझे सूर्य सेवियों की पाक-विधि पुस्तिका चाहिए।
मेरा नाम ____________________
मेरा पता ____________________
____

सूर्य एग्रोइल्स लिमिटेड
3, सिंधिया हाउस, जनपथ,
नई दिल्ली-११०००१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५९ अंक १४ ३१ जुलाई, १९८८

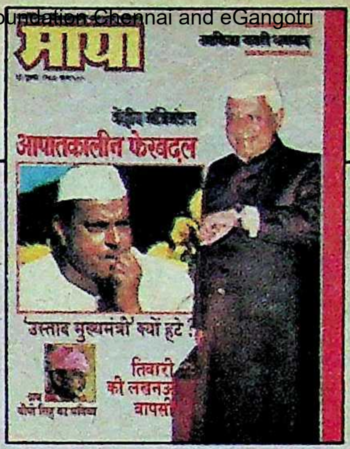

आवरण कथा

२९

गोरखपुर के छोटे से गांव हरनही के गरीब किसान के बेटे वीर बहादुर सिंह एक मामूली कांग्रेस कार्यकर्ता से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जो देश की राजनीति का नियंता है। इतना ही नहीं, पहली चार सरकारों को छोड़कर बाद में बनीं १४ सरकारों में उनकी सरकार सर्वाधिक लंबे कार्यकाल (१००५ दिन) तक टिकी रही। वीर बहादुर में कौन-सी महारत है कि वह प्रदेश के सर्वोच्च पद पर तो पहुंचे ही, अब केंद्र में संचार मंत्री भी बन बैठे हैं?

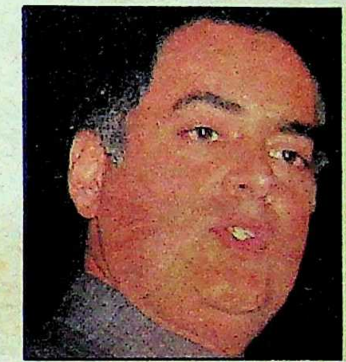

मंत्रिमंडल में फेरबदल

केंद्रीय मंत्रिमंडल में २५ वां फेरबदल क्या राजीव सरकार को उस संकट से उबार पायेगा जो उपचुनावों के नतीजों से उजागर हुआ है? ४५

नारायण दत्त तिवारी

तिवारी को सर्वाधिक सक्षम समझकर उप्र की गद्दी सौंपी गयी है या उनका कद छोटा करने की यह कोई गहरी चाल है? ४१

धनबाद माफिया

देश के सर्वाधिक धनी और आतंकित शहर धनबाद के बेताज बादशाह माफिया सरदारों पर क्या केंद्र सरकार अंकुश लगा पायेगी? १७

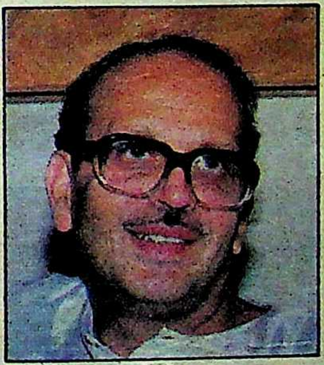

वीपी सिंह का भविष्य

इलाहाबाद उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या संपूर्ण विपक्ष वीपी सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है? ७४

शरद पवार

आठ वर्षों बाद शरद पवार को महाराष्ट्र की गद्दी सौंपने के पीछे कांग्रेस-इ की क्या रणनीति है? ६६

श्रीदेवी

फिल्म-तारिकाओं में सर्वोच्च स्थान बरकरार रखनेवाली श्रीदेवी से 'माया' का विशेष साक्षात्कार: ९०

दिल्ली दरबार/पुरस्कार की सजा १०
फोटो फीचर १३
अभिमत/राजनीति करवट ले रही है: मधुलिमये २४
विदेश २६
मध्यप्रदेश/अर्जुन सिंह की प्रेस पर कोप दृष्टि ४९
राजस्थान/सरकारी संरक्षण में फर्जी डिग्री का धंधा ५०
प्रतिभा/ प्रशांत उपाध्याय ५३
बिहार/ जहानाबाद के भाग्य में रक्तपात ५४
कर्नाटक/ जनता पार्टी: विभाजन के कगार पर ५९
पश्चिम बंगाल/ अशोक सेन अधर में ६४
तमिलनाडु/ चुनाव का इंतजार ६८
कार्टून ७१
पड़ोस/ अफगानिस्तान और हमारे हित ७९
धनधंधा ८४
अर्थतंत्र: लाइसेंस में छूट से फायदा किसको? ८६
प्रसंगवश/लोक लेखा समिति ९४
दूरदर्शन ९८
स्त्री/ पति निंदा रस १००
बेढब १०१
परदे के पीछे १०२
व्यक्तित्व/ कविता चौधरी से बातचीत १०४

आवरण पारदर्शी

मनमोहन शर्मा
(वीर बहादुर सिंह, वीपी सिंह)
सोएनएस
(नारायण दत्त तिवारी)

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७५०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

जुलाई द्वितीय अंक

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

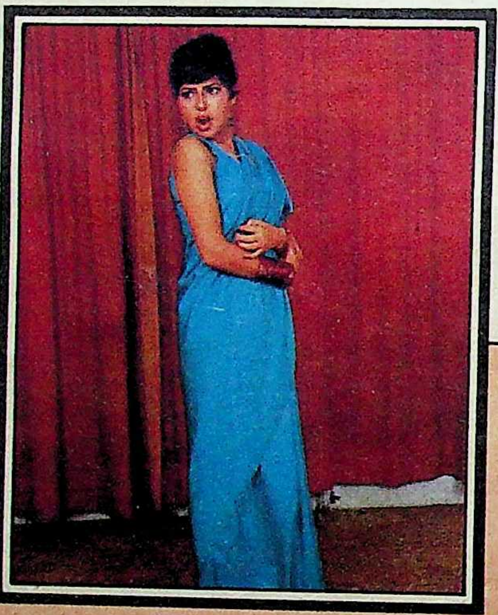

खास अंदाज में खास रचनाएं

प्रमुख आकर्षण

- भावनाओं के खिलाड़ियों से सावधान
- ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं लोग ?
- पति-पत्नी के संबंध कैसे खुशहाल हों ?
- रिमझिम-रिमझिम बरसे बदरा
- सरप्राइज विजिट
- उन्हें उपहार देना सिखाइये
- इत्र की यायावरी
- आप कितनी ईर्ष्यालु हैं ?

अन्य आकर्षण

- मेरी सुहागरात : 'मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता'
- फुरसतनामा : डार्याटिंग मुर्दाबाद ! मोटापा जिन्दाबाद !!

आवरण कथा :

प्रेम या हुकूमत : आपके पति क्या करते हैं ?

पति-पत्नी का एक-दूसरे पर अधिकार प्यार का ही दूसरा नाम है और यही दाम्पत्य जीवन का आधार है। पर अधिकार की यह भावना अक्सर पतियों में इतनी बढ़ जाती है कि एक बंधन, एक कैद बनकर पत्नियों को जकड़ लेती है। कहीं आपके पति का रवैया भी ऐसा तो नहीं है ?

- चक्रव्यूह : बेबस सुनीता
- सौन्दर्य : बरसात में सौन्दर्य की रक्षा कैसे करें ?
- वह एक अनोखी : पार्वती बरुआ : हाथी जिनके साथी
- अनुभव : जब मेरी पोल खुली
- व्यंजन : गरमागरम परोसें
- हमसफर : सुरिन्दर सिंह और पद्मा सचदेव
- कहानी : प्रेमिका संवाद/ मथुरा कलौनी
  दुनियादारी/ आशापूर्णा देवी
- अतीत : गुलाम बेगम/ के०रा० शिरढोनकर
  फिल्म : दक्षिण की आंधी : अमला

साथ ही अन्य सभी स्थाई स्तंभ

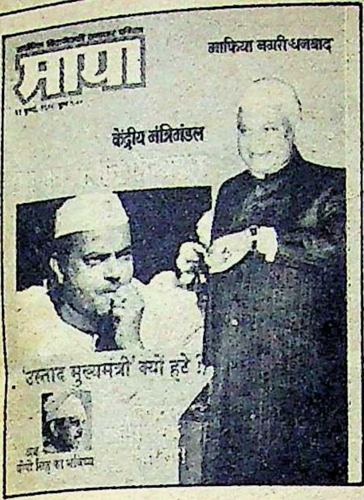

ऐतिहासिक चुनाव : कैसे जीता गया ?

'माया' के जुलाई प्रथम अंक :की आवरण कथा 'ऐतिहासिक चुनाव: कैसे जीता गया?' पढ़ी। इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव, आरंभ में लगता था कि एक इतिहास लिखेगा परन्तु जब परिणाम आये, तो पता चला कि दोनों प्रत्याशियों ने अपने लिए संसद में घुसपैठ के सारे रास्ते व साधन अख्तियार कर लिये थे। दोनों में से किसी में भी चरित्रगत एवं चुनावी हथियारगत अंतर नहीं दिखा। धन और जन की लड़ाई लड़ने वाले संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी ने पांच हजार मोटर साइकिलें और अनगिनत कारें आदि दौड़ायीं। कांग्रेस के एक गेट के उत्तर में सिविल लाइंस में दो गेट तैयार करवाकर अपनी ही नीतियों का उल्लंघन किया।

यों इतिहास एक बार जरूर हर आदमी को महान बनने का अवसर देता है। राजा साहब को २३ मई को यह अवसर उस समय मिला था, जब अमिताभ ने पर्चा नहीं भरा था। सांसद होने की उनकी अभिलाषा ने इस महान ऐतिहासिक अवसर को हाथ से जाने दिया। यदि वह चुनाव न लड़ते, तो वह दूसरे गांधी या जयप्रकाश हो सकते थे। अब देखना है कि राजा आगे चलकर स्वयं राह दिखाते हैं या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय शक्तियों के आगे घुटने टेक देते हैं।

—योगेशचन्द्र मिश्र, पूर्व प्रकाशन मंत्री
इलाहाबाद छात्र संघ इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

'माया' का जुलाई प्रथम अंक मिला। आवरण कथा का प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण ठीक हुआ है। देशभक्तों ने देशद्रोहियों की फौज को परास्त करने के लिए कलियुगी राम को मैदान में उतारा था। लंका जीतने वाले बेचारे राम इलाहाबाद में मांडा के राजा का बाल भी बांका नहीं कर सके। देशद्रोहियों ने ऐसा हमला किया कि देशभक्तों की फौज के बड़बोले सेनानी केसरी, गुलाम, भगत, बहादुर-बहादुरी के साथ सिरसा फरीदाबाद की तरफ भागे, लेकिन वहां जाट रेजीमेंट ने उनका पीछा करके गोधरा होते हुए कच्छ की खाड़ी में पनडुब्बी समेत डुबो दिया। ऊधमपुर में महाभारत के भीम ने कलियुगी राम को वायुदूत में बिठाकर वापस उमरगांव की नौटंकी में भेज दिया है। अब देशभक्तों की फौज के पास फेयरफेक्स फेरा बचा है। उनको तमिलनाडु की द्रविण सेना बंगाल की खाड़ी में डुबोने के लिए तैयार बैठी है।

—बस्तीमल सुराणा, साहूकारपेठ,
कलाती, पील्ले स्ट्रीट, मद्रास

इलाहाबाद चुनाव में वीपी सिंह की शानदार जीत से यह साबित हो गया है कि असली शहंशाह कौन है ? वीपी ने चुनाव में धनशक्ति के बजाय जनशक्ति का उपयोग कर विजयश्री हासिल की। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि धन और आतंक के बढ़ते प्रभाव लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक हैं। भारतीय राजनीति में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ राजा मांडा ने जो संघर्ष शुरू किया है, उसे हर देशभक्त का समर्थन मिलेगा।

—सुरेश कुमार सोनी, रतनपुर,
बिलासपुर, मप्र

अनुमान सच साबित हुए

'माया' का जून अंक (द्वितीय) प्राप्त हुआ। इस अंक में अगर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, तो वह है आपकी पत्रिका द्वारा दिये गये अनुमानों का सत्य साबित होना। जैसे 'छपरौली एवं टांडा में विपक्ष का जोर', 'इलाहाबाद में वीपी सिंह का पलड़ा भारी', 'राजस्थान में विपक्ष की आपसी फूट का कांग्रेस को फायदा होगा, 'लश्कर में भाजपा का जोर' वगैरह-वगैरह। उक्त सारे अनुमान अक्षरशः सत्य साबित हुए हैं। आपकी पत्रिका ने यह साबित कर दिया है कि 'माया' का कोई सानी नहीं है। यानी सत्य ही 'माया', है व 'माया' ही सत्य है।

—आरके साण्डेरा
खांदू कालोनी, बांसवाड़ा, राज०

'माया' के जून द्वितीय अंक की आवरण कथा में इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की यथार्थ स्थिति पर आपकी टिप्पणियां सटीक एवं बेबाक लगीं। किंतु खेद है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 'माया' भी अन्य पत्रिकाओं की भांति राजनेताओं के स्तुतिगान में दिलचस्पी लेने लगी है। माया को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी यह मानसिकता उसकी लोकप्रियता को ठेस पहुंचा सकती है। वैसे अभी तक तमाम राजनीतिक पत्रिकाओं में 'माया' का वर्चस्व रहा है, क्योंकि वह निष्पक्ष पत्रकारिता की पक्षधर रही है। किंतु इधर कुछ दिनों से उसकी भूमिका भी संदिग्ध होती जा रही है।

—वेद प्रकाश पांडेय, ११५ लक्ष्मण-
राव रोड, बंगलौर

राजा माण्डा के अनुसार, अमिताभ के चुनाव में न उतरने से वह नैतिक रूप से जीत चुके हैं, जबकि वास्तव में वह अमिताभ से मानसिक रूप से हार चुके हैं। वीपी ने दावा किया था कि चाहे कुछ भी हो, अमिताभ चुनाव जरूर लड़ेंगे। टीवी पर दिये इण्टरव्यू में उन्होंने जो भी कहा, वह उनकी खोखली मानसिकता का प्रतीक है। हर चुनाव में लोहे के चने चबाने वाली कांग्रेस को सिर्फ अमिताभ ने ही सर्वाधिक दो लाख मतों से विजयी कराया था। इस अंक में राजा की तरफदारी करके आपने अपनी निरपेक्षता की विशेषता पर घातक प्रहार किया है। फोटो फीचर में अमिताभ का चित्र रंगीन होना था।

—संतोष सोनी, मोतीराम सोनी,
रामगली बालाघाट, म प्र

ईर्ष्या क्यों ?

३० जून की 'माया' में बूटा सिंह का साक्षात्कार पढ़कर महसूस हुआ कि वास्तव में बूटा सिंह में सही वक्त पर सही निर्णय लेने की विशेष क्षमता है। तभी तो वह आज देश के गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। भले ही वह विवाद के घेरे में हों। वैसे भी भारतीय समाज की यह कमजोरी रही है कि यहां एक दूसरे की सफलता को कोई फूटी आंखों नहीं देखना चाहता है। बूटा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बूटा सिंह ही तो हैं, जिन्होंने राष्ट्र के सामने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। फिर सफलता की ओर बढ़ने पर उनसे ईर्ष्या क्यों ?

—मोती लाल राम
मंझौल, बेगूसराय

जैट
और
बोस्की
सिर्फ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित

'माया' के प्रति स्थानीय नेताओं का नजरिया

मैं 'माया' का पुराना पाठक हूं। जो कुछ इसमें छपता है, उसे मैं रुचि लेकर पढ़ता हूं, क्योंकि माया की खोजबीन निष्पक्ष और तथ्यपरक होती है। राजनीति में भी मैं थोड़ी बहुत दखल रखता हूं और अकसर राजनेताओं से मिलता रहता हूं। वे राजनेता भी 'माया' की रिपोर्टों को खासी तरजीह देते हैं। लेकिन इलाहाबाद के कुछ राजनेताओं से जब भी कभी बातें हुई और 'माया' का जिक्र आया, तो वे फौरन फतबा देते हैं कि 'माया' सरकार विरोधी है। पता नहीं उनको ऐसा प्रचार करने से क्या मिलता है!

जहां तक मेरा मत है 'माया' के दो उद्देश्य हैं—देशहित और निष्पक्ष जायजा। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी सत्ता में आये थे, तो 'माया' ने राजनीति में नये खून के प्रवेश से देश में उठी उत्साह और आशा की नयी लहर पर लगातार कथाएं प्रकाशित की थीं। उस समय विपक्षी खेमों में यह कहा जाने लगा कि 'माया' कांग्रेस की पत्रिका है।

जहां तक इलाहाबाद का सवाल है, १९८४ में 'माया' ने पहले ही बता दिया था कि अमिताभ की जीत होने जा रही है और वही हुआ। इस बार भी चुनाव के पहले वाले अंक (३० जून) में बता दिया था कि कांग्रेस हारने जा रही है—और वही हुआ। इससे पहले २९ फरवरी के अंक में 'माया' ने स्थानीय कांग्रेस संगठन में गुटबाजी के बारे में जो कुछ कहा था, वही बात अब चुनाव के बाद स्वयं कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। 'माया' के पास जो जानकारी थी, वह सरकार के खुफिया विभाग के सूत्रों के पास भी नहीं थी।

'माया' जनता की नब्ज पहचानती है और उसको साफगोई से कहती है। साफगोई का संबंध किसी पक्ष-विपक्ष से नहीं होता और यह बात मुगालतों में जीने वाले राजनेताओं को समझनी चाहिए। स्थानीय नेताओं की बातों को सुनकर मुझे यह लिखने को बाध्य होना पड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि आप इस पत्र को छापें।

—एल के गोस्वामी
इलाहाबाद

'माया' नेता के नहीं, जनता के साथ

प्रेस के मामले में सियासी लोगों का नजरिया कितना तंग होता है, इसकी एक मिसाल मुझे 'माया' के सिलसिले में याद आ रही है। २९ फरवरी के अंक में 'माया' ने एक सर्वे शाया किया था, जिसमें राजा साहिब के मुकाबिले फिल्मी अदाकार अमिताभ बच्चन की मकबूलियत ज्यादा दिखायी गयी थी। उस समय राजा साहब से मिलने का मौका मिला, तो लगा वह 'माया' से काफी खफा हैं। मुझे इसकी भी खबर है कि उन्होंने उस समय 'माया' को इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन एक अंग्रेजी की समाचार पत्रिका से बातें करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। अब राजा साहब को 'माया' का ३० जून का अंक देखकर पता लग गया होगा कि 'माया' वह खबर देती है, जिसकी किसी को खबर नहीं होती। मैं तो कहूंगा 'माया' जनता के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं।

—इकबाल हामिद (पत्रकार)
पुरानी दिल्ली

खंडन

आपके १५ जुलाई, १९८८ की 'माया' में पेज नं० १३ पर यह लिखा है कि सुनील शास्त्री मां कल्याणी की पूजा कर रहे हैं। वह मंदिर कल्याणी माई का न होकर खेमा माई का है।

—पंकज पुरवार
१३, लोकनाथ, इलाहाबाद

'माया' का १५ जुलाई '८८ का अंक देखा। पेज ६० पर मध्य प्रदेश के खरसिया विधान सभा उपचुनाव के संबंध में प्रथम पैरा की दसवीं लाइन में आपने यह लिखा है कि यह सीट इंका विधायक लक्ष्मी प्रसाद पटेल के निधन से रिक्त हुई थी। जबकि खरसिया विधान सभाई सीट इंका विधायक लक्ष्मी प्रसाद पटेल द्वारा इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी।

—दयाशंकर मिश्र, जवाहर नगर,
सतना

(इस भूल के लिए हमें खेद है—स०)

खयालात

मंत्रिमंडल महज रद्दी की टोकरी होकर रह गया है।—**वीपी सिंह, लखनऊ में**

हर बात के लिए दिल्ली नहीं दौड़ूंगा।—**महाराष्ट्र के नयें मुख्यमंत्री शरद पवार**

विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का जहां तक सवाल है, इसमें उनके न चाहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।—**चंद्रशेखर, पटना में**

योद्धा कभी हारता नहीं।—**सुनील शास्त्री अपनी पराजय पर**

मेरी पार्टी दोनों ही सांपों—कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए नेवला है।—**बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशी राम**

बहुत अंधेरे में जुगनू भी सहायता देता है।—**वीपी सिंह की जीत पर लोकदल-ब अध्यक्ष बहुगुणा**

अंग्रेजी के अखबार 'हिंदू' में बोफोर्स सौदे में ली गयी दलाली के अकाट्य सबूत देखकर सरकार को सांप सूंघ गया है।—**'जनसत्ता' की संपादकीय से**

मैं नन नहीं बनना चाहती।—**शादी के संबंध में पूछे जाने पर पीटी उषा, 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में**

चंद्रशेखर

शरद पवार

अमजद अली खां

श्रीदेवी

इस देश में अकेला मैं ही गांधीवादी हूं।—**गोरखा लिबरेशन फ्रंट के नेता सुभाष घीसिंग 'इंडियन पोस्ट' में**

मैं कोई कांग्रेसी नहीं, जो दोतरफा बात करूं।—**प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु**

यदि हम हथियारों की होड़ रोकने में असफल रहे, तो विश्व विनाश के कगार पर पहुंच जायेगा।—**सोवियत संघ के महासचिव गोर्बाचोव**

यह बड़े दुख की बात है कि अन्नादुरै और पेरियार जैसे महान नेताओं का राज्य दो पेटीकोटों के अंदर शरण ले।—**डीएमके के करुणानिधि**

अगर सरकार ने यह आग्रह नहीं माना, तो हमारा सर्वनाश हो जायेगा।—**पंजाब सरकार को अपने समर्पण और पुनर्वास के संबंध में भेजे गये खत में एक अज्ञात आतंकवादी**

अब वक्त आ गया है कि दिवंगत एमजी रामचंद्रन द्वारा गठित अविभाजित दल के सदस्य एक हो जायें और तमिलनाडु में एक 'एमजीआर' सरकार बनायें।**—अमरिका जाते समय, अन्नाद्रमुक की नेता जानकी रामचंद्रन**

हिंदुस्तानी संगीत वह पौधा है जो हर जगह नहीं उग सकता।—**हिंदुस्तानी संगीतकारों के विदेश में बसने पर उस्ताद अमजद अली खान**

मेरी नींद इतनी कच्ची नहीं कि सोनम के आने से उड़ जाये।**—श्रीदेवी**

डायमंड
पाकेट
बुक्स में

पेश करते हैं –
एक महान उपन्यासकार
विक्की आनन्द
का नया जासूसी उपन्यास
धुंध 6/-

- लेखक का दावा है कि यह उपन्यास आपको पसंद आयेगा।
- एक नई किस्म के जासूसी उपन्यासों की परम्परा इस उपन्यास से शुरू होगी।
- विक्की आनन्द के उपन्यासों में रहस्य, रोमांच और इन्वेस्टीगेशन का अनूठा समन्वय है कि आप उपन्यास को एक ही बार में पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ पायेंगे।

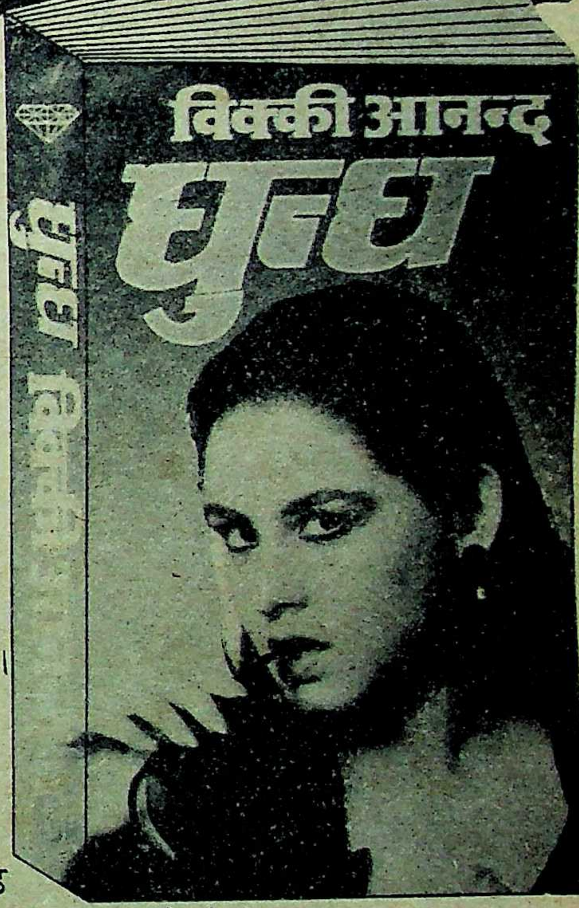
विक्की आनन्द
धुंध
धुंध
विक्की आनन्द

नकाब
समीर
नकाब
6/-

लाखों पाठकों के प्रिय उपन्यासकार
समीर
का नया उपन्यास
नकाब 6/-

सस्पैंस थ्रिल और एक्शन के जादूगर
राहुल
का नया रोमांचकारी उपन्यास
दोषी कौन

राहुल
दोषी
कौन
दोषी कौन
6/-

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि. 2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

गमगीन वीरबहादुर

उप्र मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वीरबहादुर सिंह काफी गमगीन हैं। लेकिन उनसे कई गुना दुखी हैं, उनके दरबारी। अब वीरबहादुर प्रति दिन औसतन अपने आदमियों की दो दर्जन सिफारिशें उप्र के अधिकारियों से करते हैं। लेकिन उसमें काम केवल ३-४ का ही हो पाता है। वीरबहादुर के समर्थक इससे बहुत परेशान हैं। वीरबहादुर के संचार भवन स्थित मंत्रालय में ज्यादातर दक्षिण के अधिकारी हैं। वे भी वीरबहादुर को टेलीफोन लगाने जैसे मामूली काम के लिए भी टाल देते हैं। इसीलिए वह इस चक्कर में हैं कि कुछ अधिकारी उप्र से ले आयें।

वीरबहादुर सिंह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द सैम पित्रोदा हो रहे हैं। वह प्रधानमंत्री के संचार सलाहकार हैं। उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। सैम पित्रोदा ने वीरबहादुर को साफ संकेत दे दिया है कि वह इन योजनाओं में अड़ंगा लगाने की कोशिश न करें। उनको अगर कोई परेशानी हो, तो वह सीधे प्रधानमंत्री से बात करें।

वीरबहादुर को उनके सलाहकार यह समझा रहे हैं कि वह सैम पित्रोदा से झगड़ा मोल लें, तो उनका मंत्रालय जल्दी ही बदल जायेगा। लेकिन वीरबहादुर का कहना है कि ऐसा न हो कि राजीव गांधी उनकी पूरी ही छुट्टी कर दें। वह सैम पित्रोदा से किसी प्रकार का पंगा लेने की मनःस्थिति में इस समय नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। फिलहाल वीरबहादुर सिंह दिल्ली के ओखला गैस्ट हाउस (जो उप्र सरकार का है) में अपने बोरिया बिस्तर जमाये हुए हैं। उनको अभी तक कोई बंगला नहीं मिला है। वीरबहादुर सिंह आजकल अपने ओखला गैस्ट हाउस में दिन में तीन घंटे तक सोते हैं। यह उनका रोज का नियम बन गया है। वह कहते हैं कि जब तक उप्र के मुख्यमंत्री थे, वह रात में केवल तीन ही घंटे सो पाये हैं। अब वह उस कसर को पूरा कर लेंगे।

पंडितजी की अधूरी साध

बाबूजी यानी इंका के वयोवृद्ध नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी की इच्छा इस बार भी पूरी नहीं हो सकी। वह पिछले कई वर्षों से यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि एक-न-एक दिन उनके लल्लू (लोकपति त्रिपाठी) को मुख्यमंत्री की कुरसी जरूर मिलेगी। बेटे को कुरसी दिलाने के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। पहले दिल्ली दरबार को चिट्ठी पर चिट्ठियां लिखीं और अंत में 'राम' के सहारे चुनाव जीतने के प्रयास की निन्दा भी कर दी थी।

२४ जून को लल्लू दिल्ली में थे। उन्हें जब पता चला कि वीरबहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह इस पद पर अपना दावा पेश करने के लिए दिल्ली दरबार जा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनसे बड़े प्रेम से बातें कीं। बात-चीत करीब तीस मिनट तक चली। लल्लू ने वे सारे कारण बताये जिनकी वजह से सुनील शास्त्री की इलाहाबाद में हार हुई थी। बातों-बातों में लल्लू ने कहा, "सर, मेरे लायक कोई सेवा हो, तो बतायें, मैं पूरी तरह तैयार हूं।"

प्रधानमंत्री मुस्करा दिये, "ठीक है बताऊंगा। तिवारीजी विदेश में हैं, जरा उनसे बात हो जाये।" लल्लू यूपी निवास लौट आये। शाम चार बजे तक वह दरबार से आनेवाले फोन का इंतजार करते रहे। करीब साढ़े चार बजे गुलाम नबी आजाद का आदेश हुआ, "लोकपतिजी आप मेरे साथ लखनऊ चलें।" यह सुनते ही लल्लू खुशी से झूम उठे, "क्या दरबार ने मेरा दावा मान लिया है," फोन पर ही उन्होंने आजाद से पूछा।

"जी नहीं, आपको लखनऊ चलकर विधानमंडल दल की बैठक में तिवारीजी के नाम का समर्थन करना है।" आजाद के इस जवाब से लल्लू का चेहरा उतर गया।

२५ जून को मंत्री-पद की शपथ लेने के बाद राजभवन के गुलाबी कक्ष में जलपान के समय लल्लू का चेहरा देखने लायक था। जो भी उनसे मिल रहा था, लल्लू उनसे बस एक ही बात कह रहे थे, "मेरे बाबू की अंतिम इच्छा शायद अब पूरी नहीं होगी।"

आजाद की हैसियत

कुछ दिनों पूर्व तक दिल्ली-दरबार में गजब का जलवा रखने वाले गुलाम नबी आजाद को अब अपनी हैसियत मालूम पड़ने लगी है। साथियों और मुखालिफों की लामबंदी से आजाद को खुद अपने अस्तित्व की चूलें हिलती नजर आ रही हैं।

मखमली मिजाज के आजाद को सांसत में डालने के पीछे उनके पिछलग्गुओं के अलावा संचारमंत्री बने उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर भी सक्रिय हैं। आजाद को महासचिव पद से हटाने की जिस मांग ने जोर पकड़ा है, उसे हवा देने का काम वीरबहादुर भी कर रहे हैं। कई केन्द्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के दो दर्जन इंका सांसद और पार्टी के दो महासचिव भी आजाद को पद से हटवाने का अभियान चला चुके हैं।

इलाहाबाद उपचुनाव में मतदान से एक दिन पूर्व तो आजाद के आलोचकों ने उनके खिलाफ कमर ही कस ली थी। इस उपचुनाव के बारे में आजाद द्वारा प्रस्तुत आकलन से भी वीरबहादुर सहित उनके (आजाद के) तमाम प्रतिद्वंद्वी नाखुश थे। यहां तक कि इलाहाबाद के सर्किट हाउस में १६ जून की शाम को आजाद और वीरबहादुर सिंह में जबरदस्त नोक-झोंक भी हो गयी थी। चुनाव परिणाम आने के पूर्व तक आजाद दिल्ली दरबार को सुनील शास्त्री की जीत का विश्वास दिलाते रहे थे, लेकिन १८ जून को जब राजा की जीत के आसार नजर आने लगे, तो आजाद की बोलती बंद हो गयी और वह पूरे दिन के लिए 'अंडर ग्राउंड' हो गये।

दिल्ली दरबार में इसी के बाद से आजाद का महत्व घटने लगा। उन्हें २३ जून की शाम तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि वीरबहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का आदेश राजीव गांधी से मिल चुका है। आजाद उस दिन २४-अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में कुछ गिने-चुने खबरनवीसों को बता रहे थे, "उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। वीरबहादुर मुख्यमंत्री बने रहेंगे।" आजाद ने तो यह भी कहा कि आप लोग चाहें, तो इस खबर के साथ मेरा हवाला दे सकते हैं।" रोचक तथ्य यह है कि आजाद के इस बयान के ठीक १५ मिनट पहले दिल्ली दरबार वीरबहादुर को हुकुम फरमा रहा था, "आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको दिल्ली में एडजस्ट कर लिया जायेगा।"

जब आजाद को उक्त बातचीत की खबर लगी, तो वह हक्का-बक्का रह गये। उसी दिन शाम छह बजे वह पार्टी मुख्यालय में बैठे एक दूसरे महासचिव से यह कहते सुने गये, "मुझे अब अपनी हैसियत मालूम हो गयी है।" ■

मेरी दुनिया ही पलट जाती...

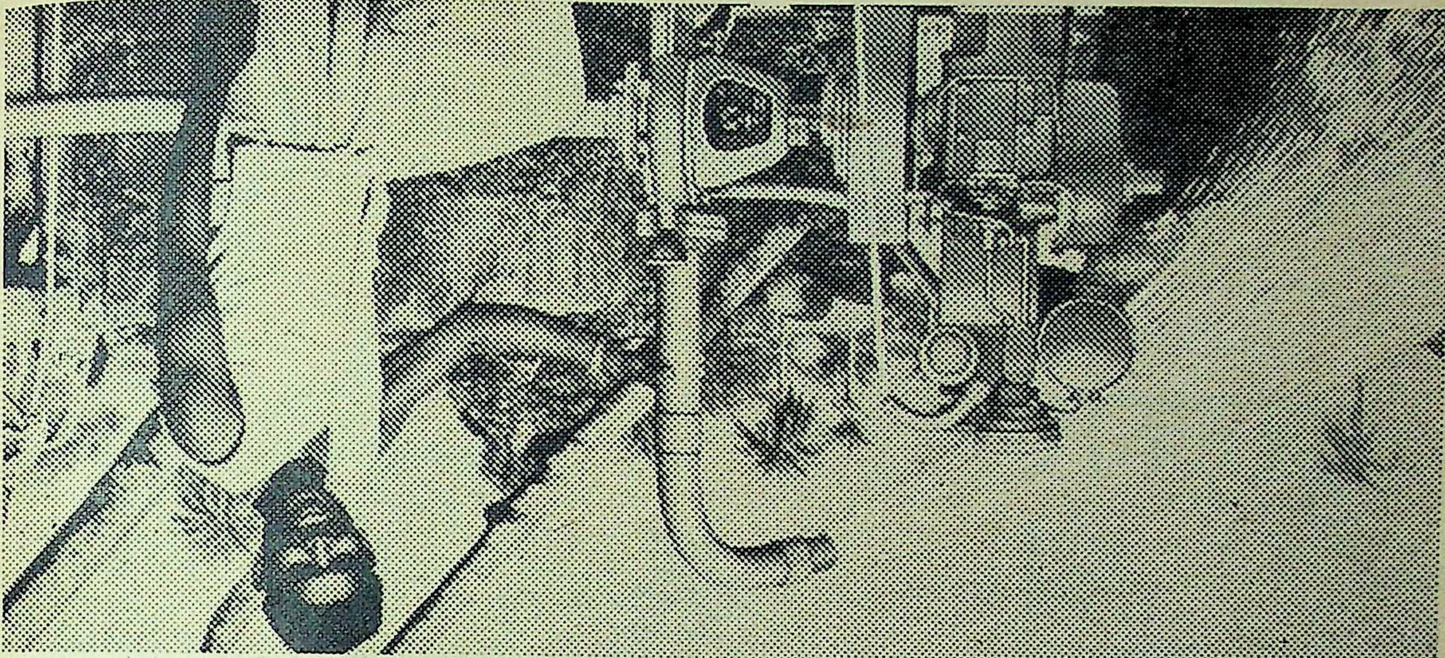

अगर मैं न्यू इन्डिया से पम्पसेट का बीमा न करवाता.

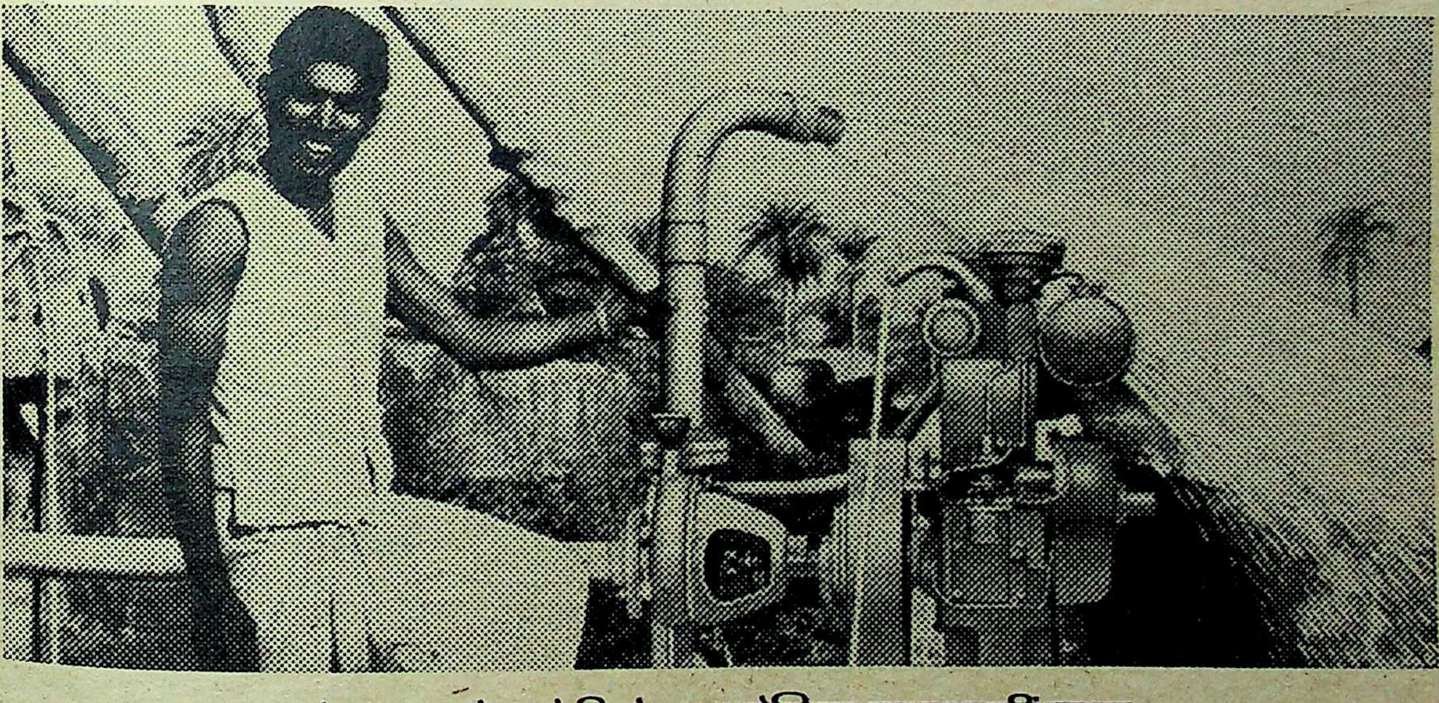

मेरा पम्पसेट चोरी हो गया लेकिन काम नहीं रुका. क्योंकि न्यू इन्डिया की बदौलत मैं नया पम्पसेट लगवा सका.

एक किसान के लिए उसका पम्पसेट कितना मूल्यवान होता है, यह बात वह और उसके परिवारवाले अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वही पम्पसेट अगर जल जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए... या चोरी हो जाए तो? ऐसे में, न्यू इन्डिया एश्योरन्स एक सच्चे मित्र की तरह उसका सहारा बनता है.

पम्पसेट बीमा – न्यू इन्डिया एश्योरन्स का मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से सालभर में 50 रुपए से 190 रुपए तक देने पड़ते हैं... बस! देशभर में न्यू इन्डिया एश्योरन्स के लगभग 1000 कार्यालय हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही एजेंट से मिलें या अपने नज़दीकी कार्यालय में पधारें.

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

जनरल इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया की एक सहायक कंपनी

पम्पसेट बिमा – नुकसान में आपका सहारा!

R K SWAMY/NIA/3573B/HIN

पुरस्कार की सजा

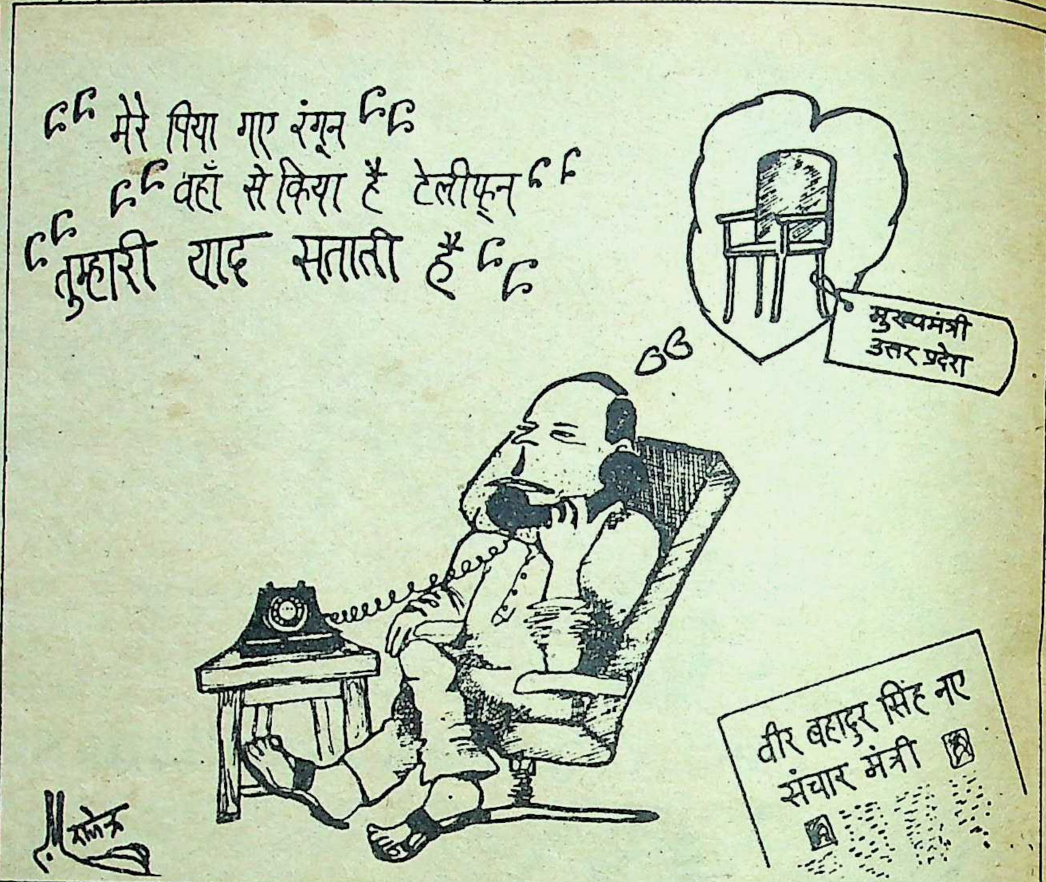

दिल्ली दरबार में भारी हड़कंप था। दरबारी अपने हाथों से कानों को दबाये चूहों की तरह बिलों की तलाश कर रहे थे। लेकिन घुप्प अंधेरे में उन्हें अपने बिल नहीं दिखायी पड़ रहे थे। दरबार का सिंहासन बत्तीसी जमीन से उखड़कर कभी दीवारों से, तो कभी छत से 'धड़ाम-धड़ाम' करके टकरा रहा था। लहू-लुहान दिल्ली दरबार सिंहासन बत्तीसी पर बैठे कुलांचें लगाते-लगाते बेहाल हो चुके थे। वह चिल्ला रहे थे, "अब मुझसे बरदाश्त नहीं हो रहा है। मैं अगर सिंहासन बत्तीसी से कूदूंगा नहीं, तो मेरे प्राण...।" दरबारी हवा में गोते लगा रहे दिल्ली दरबार का हौसला बनाये रखने के लिए नीचे से चिल्लाये जा रहे थे, "नहीं सरकार, सिंहासन बत्तीसी से कूदिएगा नहीं। जब तक आपको यह इलाहाबादी अंधड़ उठाकर न फेंक दे, तब तक आप सिंहासन बत्तीसी से गिरगिट की तरह चिपके रहिए। उसे मजबूती से पकड़े रखिए। अगर आप सिंहासन बत्तीसी से डर कर कूद पड़े, तो राजा मांडा (वीपी सिंह) उस पर चढ़ बैठेगा।" दरबारियों की इस हौसला अफजाई से दिल्ली दरबार 'हौसला बहादुर' होकर दरबार बत्तीसी से कसकर चिपक लिये।

दरबार का 'कंट्रोल टावर' इलाहाबादी अंधड़ में सावन का झूला बना हुआ था। उसका 'डाइरेक्शन' बदलने के लिए पाइप मुंह में दबाये हुए संतोष मोहन देव उस पर चढ़े हुए थे। पीछे से मदद के लिए गुलाम नबी आजाद देव को हथौड़ा थमा रहे थे। नीचे से सीताराम केसरी कमर पर हाथ रखे संतोष मोहन देव को 'डाइरेक्ट' कर रहे थे, "एक हथौड़ा जमकर टावर के 'एंटीना' पर जमा कि उसका मुंह इलाहाबाद की जगह मद्रास की तरफ हो जाये।" संतोष मोहन देव ने आजाद से हथौड़ा लेकर टावर के एंटीना पर भरपूर वार किया, तो उसका मुंह इलाहाबाद से घूमकर तमिलनाडु (वहां अभी चुनाव होने हैं) की तरफ हो लिया। जैसे टावर का मुंह इलाहाबाद से हटा, "सिंहासन खाली करो—वीपी सिंह आते हैं" का उद्घोष दिल्ली दरबार में मंद पड़ने लगा। मय दिल्ली दरबार के सिंहासन बत्तीसी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। टावर से उतरकर संतोष मोहन देव ने पसीना पोंछ कर अपने हाथ अपने असमिया सेठ (वह जो देव के साथ इलाहाबाद में था) के सामने पसार दिये। असमिया सेठ ने देव के सामने 'धनशक्ति' से भरी अटेची बढ़ा दी। देव बिगड़ पड़े, "अबे, तुझसे कहा था कि धनशक्ति मेरे घर पर रखकर आओ, तू इसे अपने साथ ले आया। यहां धनशक्ति नहीं, जनशक्ति की कमी है। मेरी वह रिपोर्ट निकाल जो मैंने इलाहाबाद एयर फोर्स क्लब में बैठकर चुसकियों के बीच बनायी थी। असमिया सेठ ने अटेची पीछे करके रिपोर्ट संतोष मोहन देव के सामने बढ़ा दी। देव रिपोर्ट लेकर दिल्ली दरबार की तरफ जब मुखातिब हुए, तो मोती लाल वोरा डाक्टरों की पूरी टीम लिये दिल्ली दरबार की मरम्मत में जुटे हुए थे। चेहरे की झाड़ पोंछ का काम सरोज खापर्डे अपने जिम्मे लिये हुए थीं। देव ने आगे बढ़कर मोती लाल वोरा को पीछे धकिया दिया, "यह सब फुरसत में करना। अभी मुझे रिपोर्ट लेकर दिल्ली दरबार पर चढ़ लेने दो। ज्यादा देरी हो गयी, तो रिपोर्ट जायेगी चूल्हे-भाड़ में और वह हिसाब-किताब के लिए मुझ पर चढ़ बैठेगा।" वोराजी तो सहम कर पीछे हो लिये। लेकिन सरोज खापर्डे दिल्ली दरबार के चेहरे पर आत्मविभोर होकर उसी तन्मयता से जुटी रहीं। देव ने अपना पाइप पास खड़े अपने असमिया सेठ को पकड़ा कर सरोज का जूड़ा पकड़ लिया। देव सरोज का जूड़ा पकड़ कर पीछे खींचें कि जूड़ा उनके हाथ में आ गया। सरोज को दूर-दूर तक पता ही नहीं चला कि उनके सिर से उनका नकली जूड़ा गायब हो चुका है। वह उसी तन्मयता से दिल्ली दरबार के चेहरे पर चालू रहीं। अब गुस्से में देव ने जूड़ा जमीन पर पटक सरोज के असली बालों पर हाथ मारा, तो वह 'उई अम्मा' के साथ चीख पड़ीं। देव ने पीछे से अपने असमिया सेठ से पाइप लेकर मुंह में दबाया और दिल्ली दरबार को धुआं उड़ाते हुए रिपोर्ट थमा दी, "सर इस रिपोर्ट का वीडियो कैसेट बनाकर देख लें। आपको साफ-साफ पता चल जायेगा कि वीपी सिंह ने आपको क्यों और कैसे पटकनी इलाहाबाद में मारी कि आपकी बत्तीसी हिल गयी।"

दिल्ली दरबार ने अपनी उखड़ी हुई सांस को 'कंट्रोल' में करते हुए देव को अपने चरणों में बैठ जाने का संकेत देते हुए कहा कि रिपोर्ट का तो वीडियो जब बनेगा, तब बनेगा। मुझे बताओ कि राजा मांडा ने इलाहाबाद में मुझे

धोबीपाट कैसे मार दिया? देव ने पाइप में ताजा तम्बाकू भर कर गहरा कश खींचकर दिल्ली दरबार के लहू-लुहान चेहरे पर धूएं का छल्ला फेंका, "सर, आप यह मत बोलो कि वीपी सिंह ने मुझे धोबीपाट मारा। आप बोलो कि इलाहाबाद के चुनाव से मेरा कुछ लेना-देना नहीं। यह बिलकुल 'लोकल' मामला है। वीपी सिंह ने वीर बहादुर सिंह को दुलत्ती जमायी है। मैं उसे निकाल दूंगा। वह इतना माल खाकर भी वीपी सिंह से टक्कर नहीं ले पाया। वीर बहादुर की उप्र की घोड़ा-गाड़ी (नौकरशाही) पर कोई 'ग्रिप' नहीं रह गयी है।" सांस की धुकनी चलने की वजह से दिल्ली दरबार के मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। उन्होंने हाथ के इशारे से देव की काला धुआं उगलती जुबान को रोका, "अरे उस गोरखपुरिए को नंगा करने पर उतारू हो। वह तो पैदाइशी नंगा है।— मैंने तो तुम लोगों को चुनाव में धांधली करने के लिए भेजा था! उसका क्या हुआ?" देव ने लपक कर अपनी रिपोर्ट का सातवां पन्ना खोल दिया, "सर, यह देखिए। मैंने अपनी इस रिपोर्ट में साफ-साफ बता दिया है कि हम लोग 'रिगिंग क्यों नहीं कर पाये। जिस घोड़े (नौकरशाह) पर हमने अपने सेवादल को बिठाकर रिगिंग के लिए भेजा, उसने हिनहिना कर उसे पटक दिया और घोड़ा भाग कर वीपी सिंह कैम्प में चला गया।" दिल्ली दरबार ने दबे स्वर में पूछा—"ऐसा क्यों हुआ?" देव ने पाइप से फिर धुएं का छल्ला निकाला "सर, वीर बहादुर का कहना है कि घोड़ा चारा खाकर भी मुंह फेर गया। वह और चारे (वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने) की मांग करने लगा। मैंने वीर बहादुर से कहा भी कि फौरन घोड़ों को और चारा डालो। वीर बहादुर कहने लगा कि इस बात की क्या गारंटी कि घोड़े दूसरा चारा खाकर भी मुंह नहीं फेर जायेंगे। सर, आप ही बताइये, मैं क्या करता! घोड़ा घास से यारी करने लगे, तो पूरा निजाम (प्रशासन) ही उलट जाता है।" दिल्ली दरबार ने सीने में पूरी सांस भर कर कहा, "अगर ऐसी बात है, तो इसमें इस गोरखपुरिए का ही क्या, किसी का दोष नहीं।" दिल्ली दरबार दुबारा सांस भर कर अपनी बेबसी का इजहार करें कि उसके पहले माखन लाल फोतेदार अपना इस्पाती मुखौटा लगाकर अवतरित हो गये। उनके पीछे बूटा सिंह अपनी पगड़ी संभाल हुऐ थे। फोतेदार जार्ज की तरफ मुखातिब होकर गरजे, "दरबार खाली कराओ। मेरे नथुनों में गहरी साजिश की बदबू घुस रही है।" पीछे से बूटा सिंह ने फोतेदार की हां में हां मिलायी, "घर के चिराग से घर को जला देने की गहरी साजिश।" पूरा दरबार हिल गया। घड़ाधड़ दरबार की खिड़की-दरवाजे बंद होने लगे। दरबारियों को धक्का-मुक्की देकर खदेड़ दिया गया। पूरे दरबार में 'रेड एलर्ट' का साइरन कुत्तों की तरह रोने लगा। फोतेदार ने सिगरेट का गुल झाड़ते हुए दिल्ली दरबार के कानों में फूंकना शुरू कर दिया, "सर, हिंदू ने बोफोर्स की तोप का मुंह दरबार की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली दरबार ने 'हिंदू' का नाम सुनते ही हिचकी ली, "क्या पं० कमलापति त्रिपाठी को कुछ बनाना पड़ेगा! कमलापति त्रिपाठी हम लोगों की अंदर ही अंदर काट कर रहे होंगे, इसीलिए 'हिंदू' नाराज हो रहा है। क्यों न उनके बेटे लोकपति त्रिपाठी को उप्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाये। लोकपति तो काफी लम्बे अर्से से मेरे दरबार के गेट पर अनशन पर बैठा हुआ है।" फोतेदार अपना मुंह पीटें कि उससे पहले ही दिल्ली दरबार ने पंचम में आवाज लगा दी कि 'लोकपति त्रिपाठी को अंदर बुलाओ। मैंने उसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है।" फोतेदार दिल्ली दरबार की बोलती बंद करें कि उसके पहले ही लोकपति त्रिपाठी एक जग भांग मिश्रित गन्ने का जूस पीकर दिल्ली दरबार के चरणों में लोट लिये, "सरकार, आपने मेरी और मेरे बाबू (कमलापति त्रिपाठी) की सालों की मुराद को पूरा कर दिया है। इस मुल्क के सारे 'हिंदू' आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे।" फोतेदार ने गुस्से में आकर अपना मुंह पीटना बंद करके, लोकपति त्रिपाठी की गरदन पकड़ ली और पीछे खड़े बूटा सिंह के हवाले कर दी, "बूटा, इसे बाहर गटर में फेंक दे।" दिल्ली दरबार की समझ में नहीं आया कि फोतेदार यह कौन सी कलाबाजी दिखा रहे हैं? फोतेदार ने दिल्ली दरबार के और करीब होकर सिगरेट का लच्छेदार धुआं फेंकना शुरू कर दिया, "सर, मैं मद्रास के 'हिंदू' अखबार की बात कर रहा था।" दिल्ली दरबार ने अपनी लम्बी गरदन हिलायी। फोतेदार ने कान में फिर धुआं फेका "सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं—नारायण दत्त तिवारी को दरबार से कोसों दूर फेंकिए।" दिल्ली दरबार ने सिंहासन बत्तीसी पर पलथी मारकर फोतेदार से पूछा, "उस नयी दिल्ली तिवारी को दरबार से कोसों दूर क्यों फेंकूं? अरे वह तो मेरा सेवक है।" फोतेदार ने दांत किटकिटा कर कहा, "अरे सर, आप समझते नहीं हैं। मैं उसका इलाहाबाद में सहपाठी रहा हूं। उसकी रग-रग मेरी उंगलियों पर है। उसने आज तक वीपी सिंह के खिलाफ सपने में भी एक शब्द नहीं बोला है। वह अगर दरबार के करीब रहा, तो आपके सिंहासन बत्तीसी को खतरा बना रहेगा।" दिल्ली दरबार का चेहरा पीला पड़कर प्रश्नचिह्नों से बुरी तरह घिर गया। बूटा ने लपक कर फोतेदार की बात को आगे बढ़ाया, "दरबार में बहुत गहरी साजिश चल रही है, सर। नारायण दत्त तिवारी सोच रहा है कि इस बार बोफोर्स की तोप से गोला छूटेगा, तो आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे और वह उस पर चढ़कर बैठ जायेगा।" दिल्ली दरबार को ठंडा पसीना आ गया और वह चीख पड़े, "अरे, अभी-अभी तो नयी दिल्ली तिवारी मेरे सामने गिड़गिड़ा कर लंदन भाग गया है। उसे पकड़ो।"

"सर, मेरा सब कुछ जल गया है। मुझे यह सजा न दी जाये।" पास ही खड़े फोतेदार ने वीर बहादुर को आंख मारी, तो बूटा सिंह ने लपक कर गोरखपुर नरेश के कान में फुसफुसा दिया, "अरे, टेलीफोन-पोल पर चढ़ने-उतरने की सजा का मतलब है कि दिल्ली दरबार ने तुझे संचार मंत्रालय दे दिया है।"

बूढ़ा सिंह ने तुरन्त दरबार के कंट्रोल रूम में घुसकर बेतार पर तार कर दिया, "नारायण दत्त तिवारी लंदन भाग रहा है। मेरे गुप्तचरों की पूरी टीम उसको घेर ले।" इसी बीच परदे के पीछे छिपे गोरखपुर नरेश वीर बहादुर सिंह प्रकट हो गये। दिल्ली दरबार के चरणों में गिरकर वीर बहादुर ने दहाड़ मार कर रोना शुरू कर दिया, "सरकार, मेरा तो सब कुछ जल कर राख हो गया। हुजूर, अगर आप तिवारी को मेरी कुरसी पर बिठा देंगे, तो मुझे उसकी कुरसी पर बिठा दें।" दिल्ली दरबार बिगड़ पड़े—"नहीं, मैं तुझे सजा दूंगा।" वीर बहादुर ने 'सजा' के नाम पर अपनी बोटी-बोटी कंपायी। दिल्ली दरबार ने सिंहासन बत्तीसी पर बैठे-बैठे पीछे घूमकर पूछा कि इसको क्या सजा दी जाये? पीछे से कई लोगों ने हंसते हुए कहा, "सर, इसको टेलीफोन के पोल पर उतरने-चढ़ने की सजा दे दीजिए।" दिल्ली दरबार ने कहा, "ठीक है। हे गोरखपुरिये तू टेलीफोन के पोल पर चढ़ने-उतरने की सजा भुगतेगा, क्योंकि तूने मुझे इलाहाबाद जीतकर नहीं दिया।" वीर बहादुर सिंह फफक कर रोने लगे, "सर, मेरा सब कुछ जल गया है। मुझे यह सजा न दी जाये।" पास ही खड़े फोतेदार ने वीर बहादुर को आंख मारी, तो बूटा सिंह ने लपक कर गोरखपुर नरेश के कान में फुसफुसा दिया, "अरे, टेलीफोन-पोल पर चढ़ने-उतरने की सजा का मतलब है कि दिल्ली दरबार ने तुझे संचार मंत्रालय दे दिया है।" वीर बहादुर ने चुप होकर कनखियों से बूटा सिंह को देखा और धीरे से कहा, "मैं जानता हूं कि टेलीफोन के पोल पर चढ़ने-उतरने की सजा का मतलब है— संचार मंत्रालय। लेकिन अपने मूर्ख होने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।" वीर बहादुर ने फिर से फफक कर रोना शुरू कर दिया।

—दरबारी लाल

३१ उपचुनाव और होने हैं

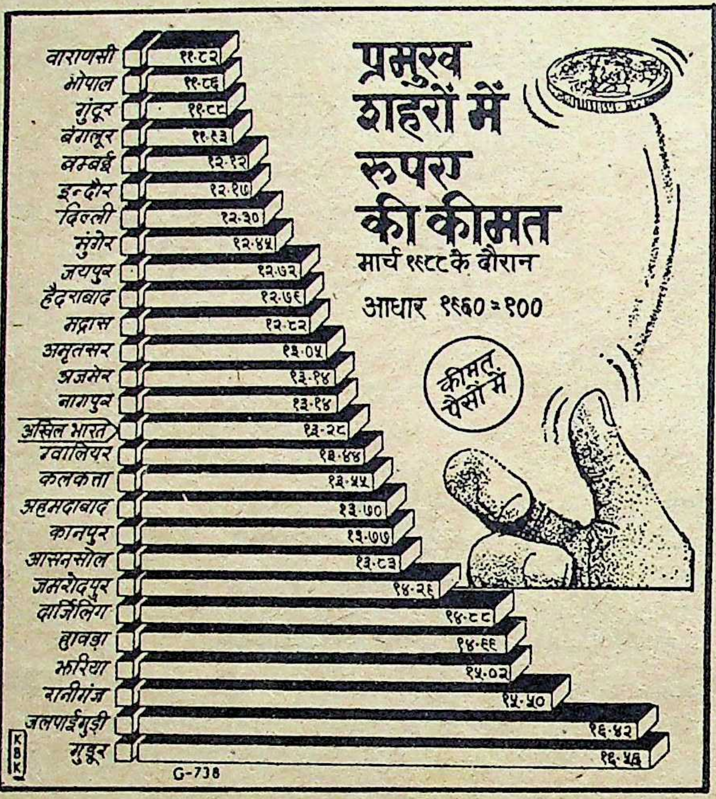

आम चुनाव होने में अभी १८ महीने बाकी हैं, लेकिन इस अवधि में १२ लोकसभा और १९ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रूप में राजीव गांधी की सरकार और विपक्ष के बीच एक बार और शक्ति परीक्षण हो सकता है। १६ जून को हुए ७ लोकसभाई और ११ विधानसभाई उपचुनावों के समय ही ११ लोकसभा [तिरुपति (आंध्र प्रदेश), भागलपुर, श्योहर, सासाराम (बिहार), कालीकट (केरल), अकोला (महाराष्ट्र), नागालैण्ड, केंद्रपाड़ा (उड़ीसा), भदुरई, करूर (तमिलनाडु) और बागपत (उत्तर प्रदेश)] सीटें खाली थीं। अर्जुन सिह द्वारा खरसिया (मप्र) विधानसभा उपचुनाव जीतने से उनकी दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट भी खाली हो गयी है।

कांग्रेस-इ के शंकरलाल और संयुक्त विपक्ष के शांति पटेल द्वारा क्रमशः पाली और गोधरा लोकसभा उपचुनाव जीतने के कारण राजस्थान और गुजरात की उनकी विधानसभा सीटें खाली हो गयी हैं। इनके अतिरिक्त जिन १७ विधानसभाई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वे हैं—प्रतिपाडु (आंध्र प्रदेश), सालीबारा दक्षिण (असम), सोनबरसा, झंझनपुर, चायबासा शाहपुर और हुसैनाबाद (बिहार), भद्रान (गुजरात), बागपल्ली (कर्नाटक), दुर्ग, इंदौर (मध्य प्रदेश), सिमना (त्रिपुरा), गोविंदनगर और शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश), नेरावी (पांडीचेरी), मालवीय नगर और शकूर बस्ती (दिल्ली महानगर परिषद)। नियमानुसार यदि आम चुनावों में एक वर्ष से कम का समय बाकी रहता है, तो उपचुनाव नहीं कराये जाते।

भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के आकलन के अनुसार भारत में कुल एक खरब ७० अरब ४६ करोड़ टन कोयले का सुरक्षित भंडार होने का अनुमान है, जिसमें से ४९ अरब, ३७ करोड़ ६० लाख टन के भंडारों का पक्का पता लग चुका है। विहार में सर्वाधिक ५७ अरब, ५७ करोड़ टन, उड़ीसा में ३२ अरब, ६६ करोड टन और पश्चिम बंगाल में ३० अरब दो करोड़ टन कोयले का सुरक्षित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है।

केंद्र सरकार ने अगले शिक्षा सत्र से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य हो जायेगा।

खरसिया विधानसभा के उपचुनाव में अर्जुन सिह की मात्र ८, ६५८ वोटों से हुई जीत को 'हार से भी बदतर' विजय कहा गया। इसके पूर्व कांग्रेस यहां हमेशा २० हजार से अधिक वोटों (१९७७ में २०४८२, १९८० में २७८११, १९८५ में २१३७९) से जीतती रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद आठ हजार से अधिक खरसियावासियों ने हारे हुए भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह जू देव का शानदार विजय जुलूस निकाला।

युद्ध और अकाल ने अफ्रीका के देशों में ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि मोजांबीक, इथोपिया और सोमालिया के ४० लाख से अधिक लोग अपने घर-बार छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो गये हैं।

भूतपूर्व रक्षा वैज्ञानिक और मानक विशेषज्ञ ब्रजभूषण विज ने मीटरिक घड़ी तैयार की है। मापन तथा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ही इस घड़ी का निर्माण किया गया है। इसमें एक घंटे में १०० मिनट, एक मिनट में १०० सेकेंड और दिन में १० घंटे होंगे तथा सप्ताह में ७ के स्थान पर ५ दिन होंगे।

दूरसंचार के महानिदेशक सत्यपाल के अनुसार भारत सरकार ने ऐसी योजना बनायी है जिसके तहत इस सदी के अंत तक अर्थात सन दो हजार ईसवी तक भारत के हर गांव को टेलिफोन सेवा उपलब्ध होने लगेगी।

पूरे देश में इस समय केवल पांच प्रांतों—बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर में ही विधान परिषदें हैं। पिछले दिनों बिहार के तीस विधायकों ने बिहार विधान-परिषद का अस्तित्व समाप्त करने के लिए विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया।

अमरीकी वैज्ञानिकों के अनुसार २४ जून को सूर्य की सतह पर एक भारी विस्फोट हुआ है, इससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में तो वृद्धि हुई, लेकिन पृथ्वी के जनजीवन पर इसका कोई असर नही पड़ा।

युधिष्ठिर के छोटे भाई नकुल द्वारा लिखित 'शालिहोत्र शास्त्र' की एक प्रति वृंदावन शोध संस्थान में उपलब्ध है। अश्व चिकित्सा से संबंधित इस ग्रंथ में घोड़ों की जातियों, रोग व लक्षणों, औषधियों और उनके प्रयोग की विधि के साथ घोड़ों के १५० चित्र दिये गये हैं।

भारतीय समुद्री सीमा में पिछले चार सौ सालों के दौरान २१० जहाज डूब चुके हैं। राष्ट्रीय समुद्र अध्ययन संस्थान ने इन जहाजों के अवशेषों का पता लगाने की योजना बनायी है। संस्थान को उम्मीद है कि जहाजों के जलमग्न अवशेषों से जहां कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां मिलेंगी, वहीं उसे कोई बड़ा खजाना भी मिल सकता है।

पोरबंदर में पिपलिया गांव के पास एक करोड़ साल पुराने समुद्री केकड़ों के जीवाश्म मिले हैं।

अमरीका इन दिनों इस सदी के भीषणतम सूखे का सामना कर रहा है। 'वाशिंगटन पोस्ट' में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस सूखे से न सिर्फ धरती सूख रही है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में एक करोड़ चालीस लाख टन ऊपरी उपजाऊ भाग बरबाद होकर धूल बनकर उड़ गया है।

खुफिया सूत्रों के अनुसार कूच बिहार जिले के सीमावर्ती डालिया नामक क्षेत्र में बंगला देश राइफल्स द्वारा गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के उग्रवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तीस-तीस गोरखा उग्रवादियों के आठ गिरोहों को वहां प्रशिक्षित किया जा चुका है और इस समय नौवां गिरोह वहां प्रशिक्षण ले रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार एक जुलाई से प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र में छह करोड़ ४५ लाख रुपए खर्च करके पांच हजार प्राथमिक विद्यालयों को रंगीन टेलीवीजन और रेडियो-टेपरिकार्डर उपलब्ध करायेगी।

—संयोजन : विनोद मिश्र

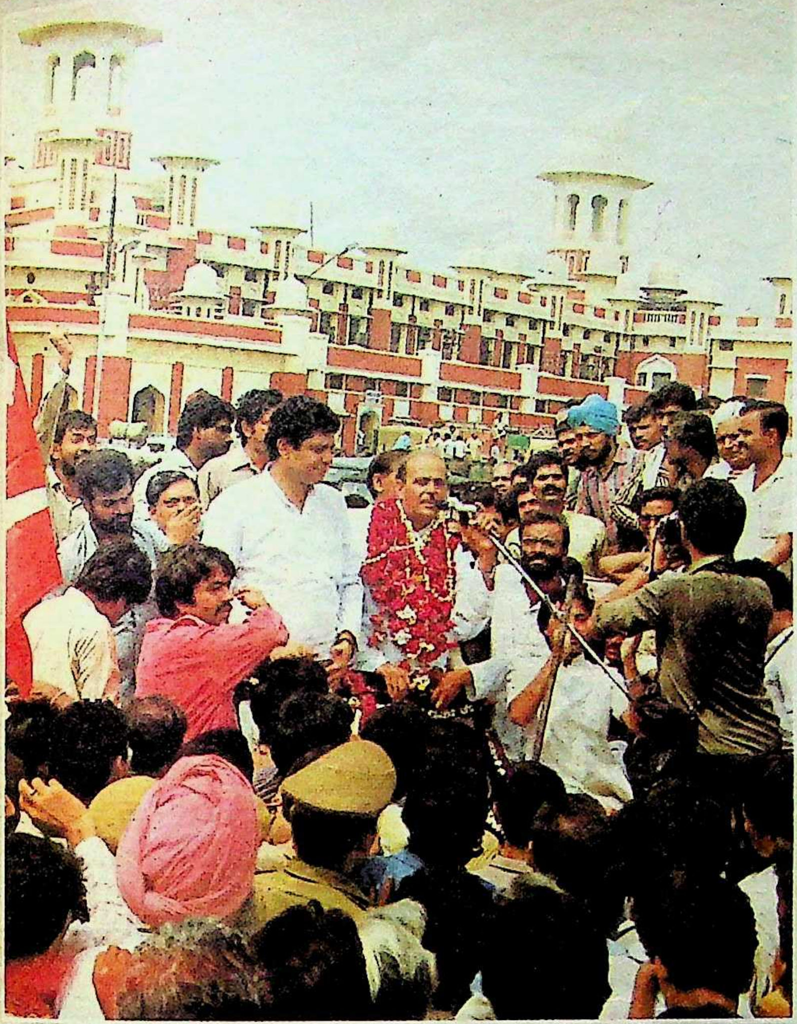

विजय-यात्रा का पहला चरण :
इलाहाबाद में इंका को पछाड़ने के बाद लखनऊ पहुंचे
वीपी सिंह चारबाग रेलवे स्टेशन पर
प्रशंसकों को संबोधित करते हुए

छाया : मनमोहन शर्मा

कारवां बढ़ता गया :
लखनऊ में वीपी सिंह का अभिनंदन जुलूस

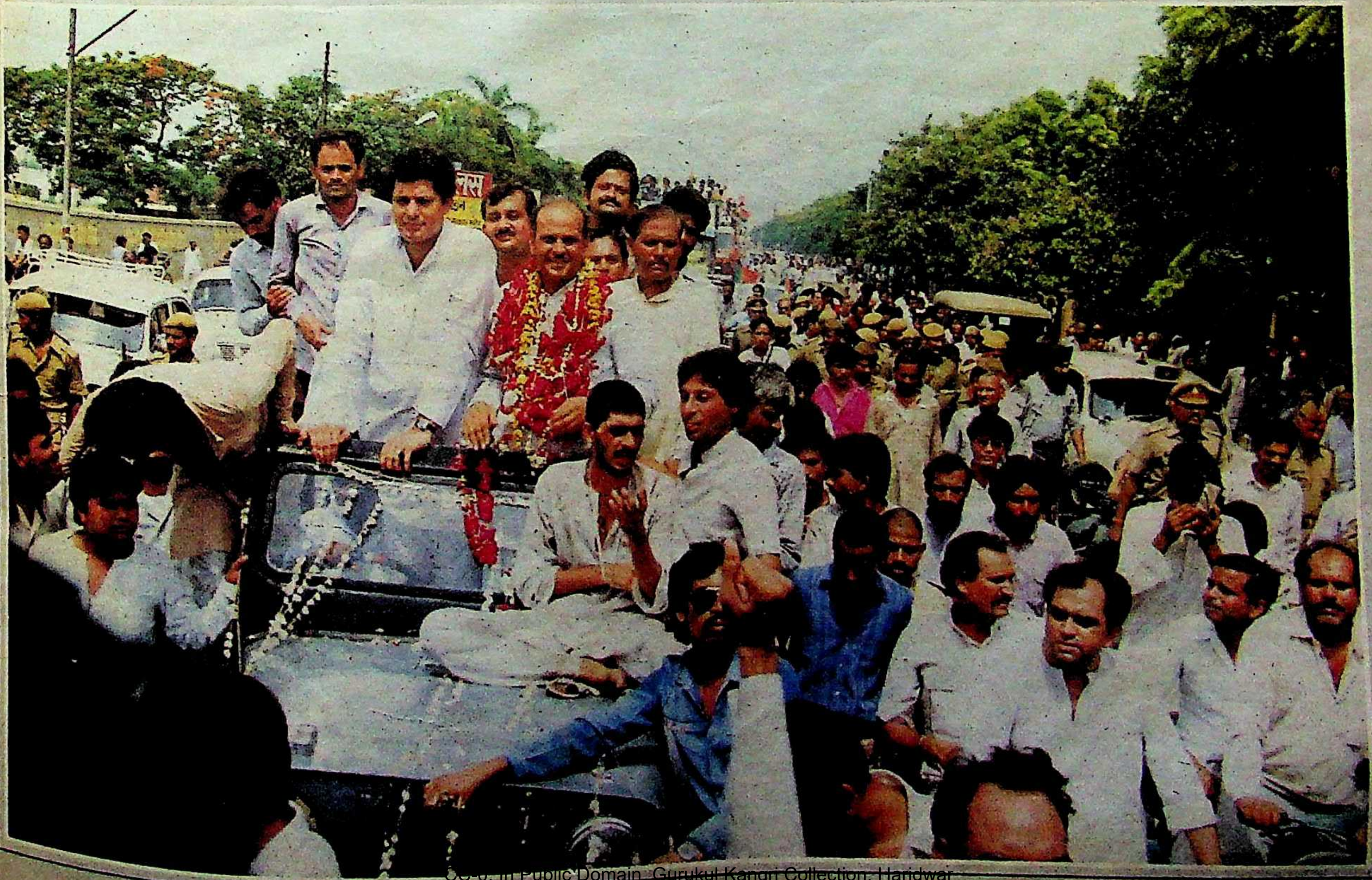

आप जीते, हम हारे : उत्तर प्रदेश के कृषिमंत्री लखनऊ में वीपी सिंह को बधाई देते हुए। अगल-बगल विद्याचरण शुक्ल और संजय सिंह खड़े हैं। (ऊपर बायें)

नेता चुनने की रस्म : नये नेता (नारायण दत्त तिवारी) के चुनाव के समय इंका विधायकों की बैठक। माइक पर प्रदेश अध्यक्ष महाबीर प्रसाद। बीच में बैठे हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और प्रेक्षक एचकेएल भगत (ऊपर दायें)

तीसरी बार : मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल उस्मान आरिफ खान से हाथ मिलाते हुए

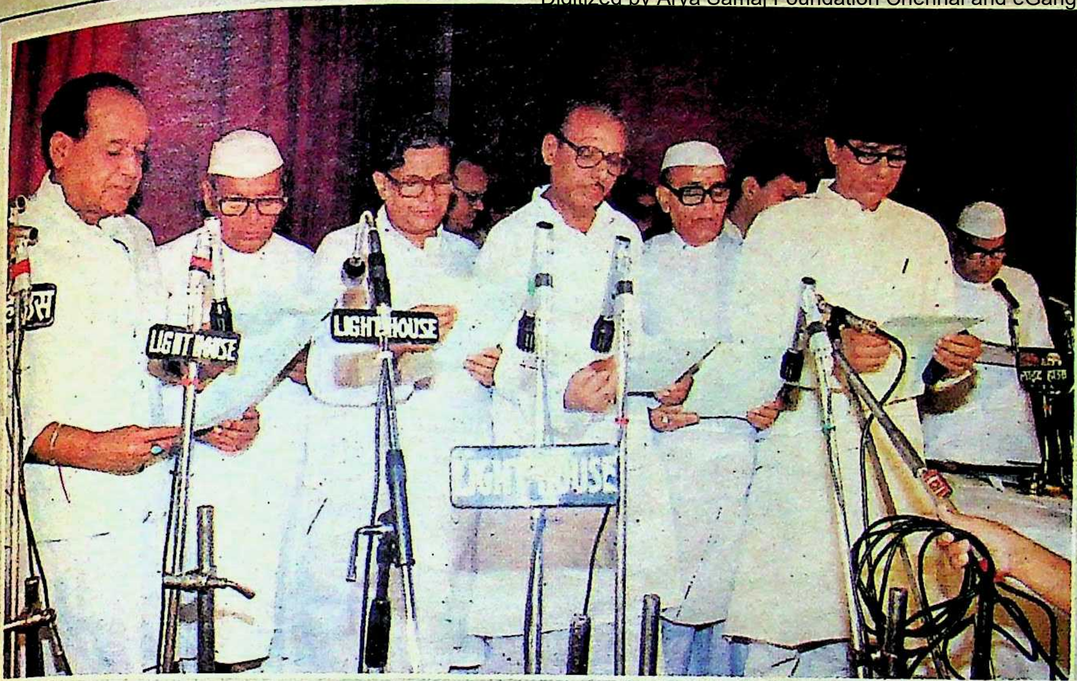

वही चेहरे : तिवारी सरकार में शामिल काबीना मंत्री (बायें से) सईदुलहसन, बलदेव सिह आर्य, अम्मार रिजवी, श्याम सूरत उपाध्याय, गोपीनाथ दीक्षित, हुकुम सिह (ऊपर)

संजय से राजीव तक : नये मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के दफ्तर में (बीच में)

कानाफूसी : दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री अरुण कुमार सिह मुन्ना मुख्यमंत्री से बतियाते हुए (नीचे)

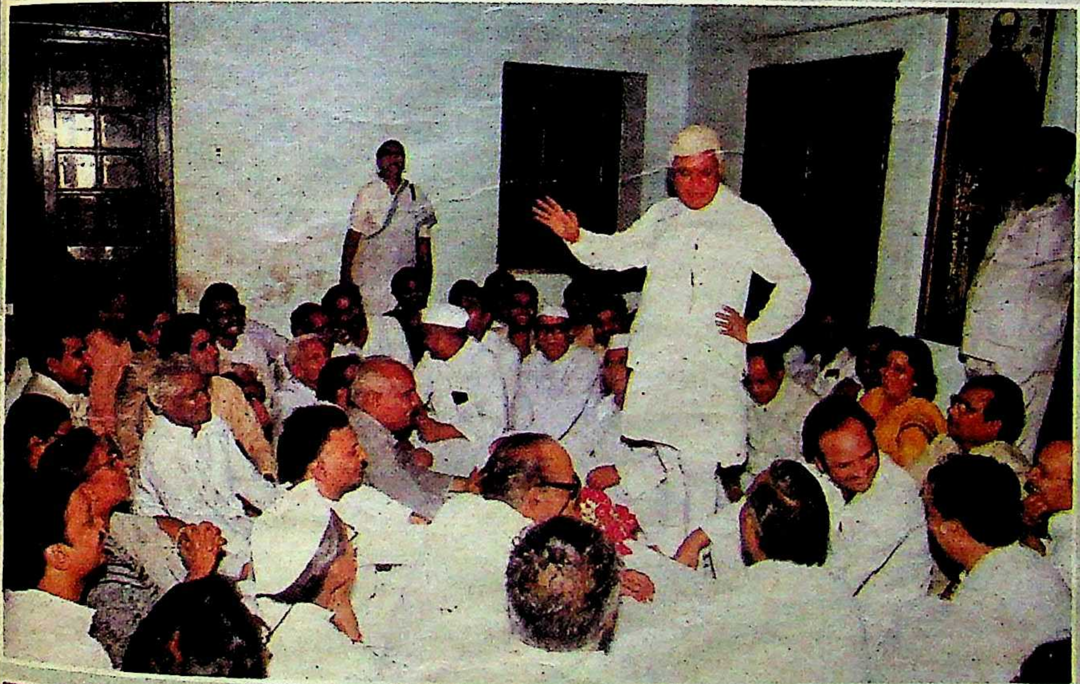

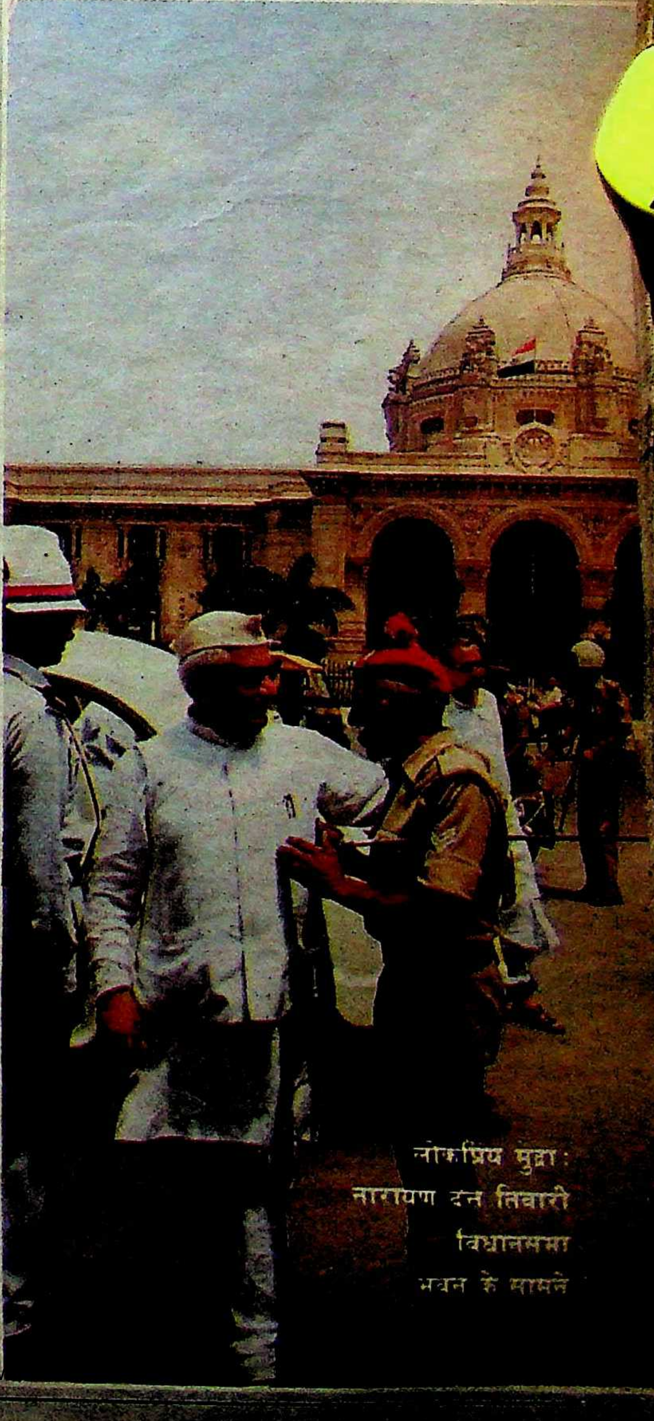

लोकप्रिय मुद्रा : नारायण दत्त तिवारी विधानसभा भवन के सामने

घूम फिर कर वही : केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नये मंत्री राष्ट्रपति भवन में

दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद... : एसबी चह्वाण वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए

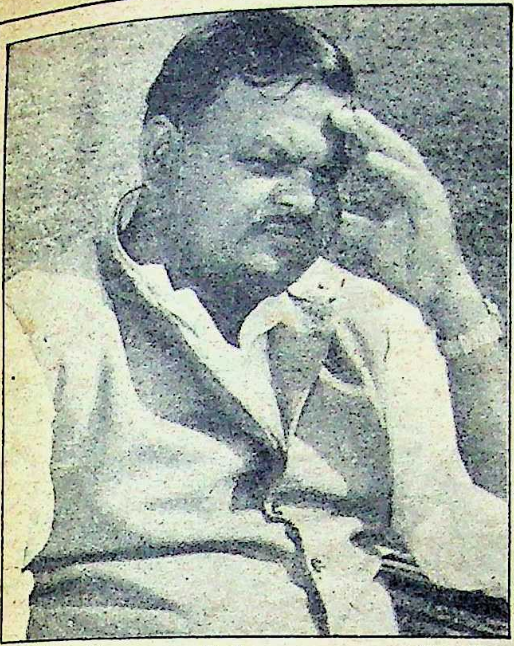

अभी जेल में : धनबाद के बेताज बादशाह सूर्यदेव सिंह

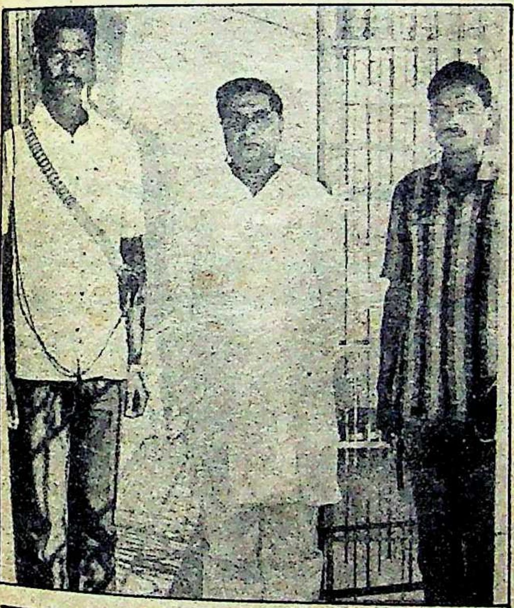

जान कब तक बचेगी ? : अंगरक्षकों के बीच अपने घर में एसके राय

राजपूतों के बाहुबली : विधान पार्षद सत्यदेव सिंह

धनबाद माफिया को दुरुस्त कौन करेगा ?

१६ जून को हुए उपचुनावों के ठीक एक सप्ताह पूर्व केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां धनबाद के माफिया सरदारों के यहां बड़े पैमाने पर छापा मारकर जब गर्व के साथ घोषणा कर रही थीं कि उन्होंने इन छापों में १५ करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता लगा लिया है, तो धनबाद का माफिया इस घोषणा पर हंस रहा था। धनबाद में जहां हाड़तोड़ मेहनत करते लाखों कोयला मजदूर हैं, तो उंगलियों पर गिने जा सकनेवाले कुछ ऐसे धनकुबेर भी हैं, जिनकी वजह से कहावत की तरह कहा जाने लगा है कि जितना धन धनबाद में है, उतना शायद भारत के किसी एक शहर में नहीं है। धनबाद-माफिया के नाम से कुख्यात इन धनकुबेरों के लिए १५ करोड़ रुपए कुछ भी नहीं। इनका नाम लेते ही लोग सिहर उठते हैं, सरे चौराहे, दिनदहाड़े, कत्ल हो जाता है, हत्यारों को सब पहचानते हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती। राजनीति और नौकरशाही में इनके दबदबे और घुसपैठ का आलम यह है कि कहा जाता है कि छापा पड़ने से पहले ही इसकी खबर उन तक पहुंच चुकी थी। बिहार का हर मुख्यमंत्री इनके सामने लाचार रहा है। शायद इसीलिए अब केंद्र सरकार ने धनबाद माफिया को दुरुस्त करने का निश्चय कर लिया है, लेकिन क्या वह कामयाब होगी ? धनबाद माफिया की राजनीतिक पहुंच और ताकत का जायजा :

बिहार के सबसे धनी शहर धनबाद पर अभी सीधे दिल्ली की टेढ़ी नजर है। केंद्र सरकार की पहल पर विगत ९ जून को आयकर विभाग, राजस्व गुप्तचर सेवा, आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने धनबाद माफिया के तमाम छोटे-बड़े ठिकानों पर सघन छापे मारे थे, लेकिन एक महीना बीतने के बावजूद धनबाद के स्वयंभू शासकों का आतंक बजाय घटने के और बढ़ता ही जा रहा है। धनबाद के एक बड़े होटल का एक मुलाजिम कहता है, "छापे के बाद से व्यवसायियों और धंधेबाजों का आना होटलों में कम हो गया है। हां, बाहर के वकीलों की आमदरफ्त धनबाद के होटलों में बढ़ गयी है। ये लोग धनबाद-माफिया द्वारा कानूनी सलाह लेने के लिए बुलाये जा रहे हैं।"

कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के कुछ ही वर्षों बाद से इस सर्वाधिक धनी शहर में माफिया-आतंक की चर्चा शुरू हो गयी थी और धीरे-धीरे स्थिति बिल्कुल चरम पर पहुंच गयी। बिहार में अब तक जितनी भी सरकारें आयीं, सभी ने दावा किया कि धनबाद से माफिया को मिटाकर छोड़ेंगे। पर जाने कितनी सरकारें आयीं और चली गयीं और धनबाद में निरंकुश माफियाराज बरकरार रहा। पर ९ जून को माफिया पर इतने भयंकर छापे ने धनबाद ही नहीं, पूरे बिहारवासियों को चौंका कर रख दिया। दरअसल, सभी यह उम्मीद खो चुके थे कि सरकार माफिया का कुछ भी बाल बांका कर सकेगी। पर राजनीति की पेंदी छाननेवालों के लिए यह छापा तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं था। ऐसा होना ही था। पर क्यों ? धनबाद माफिया से खुद सीधे निपटने की केंद्र सरकार ने क्यों ठानी ? इस सवाल का उत्तर दिग्गज राजनीतिक खिलाड़ी तो जानते ही हैं धनबाद-माफिया भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है।

छापों का मकसद : राजनीतिक खिलाड़ी इस

छापे की जड़ इलाहाबाद के उपचुनाव में तलाशते हैं। इस कयास में दम भी है, क्योंकि उस दिन बस एक ही जाति (राजपूत) के यहां छापामारी हुई। इंका के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि दिल्ली को इस बात का पूरा अंदेशा था कि इलाहाबाद उपचुनाव में अपने स्वजातीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की मदद करने के लिए धनबाद से बेशुमार धन और माफिया का पूरा सशस्त्र जत्था इलाहाबाद जायेगा। लिहाजा, चुनाव के ऐन सप्ताह भर पहले छापामारी की योजना पक्की कर ली गयी।

उस दिन ९ जून को धनबाद से इंका सांसद शंकरदयाल सिंह के अनुज विधान परिषद सदस्य सत्यदेव सिंह के धनबाद स्थित काको, कतरास, सिताबदियारा स्थित पुश्तैनी निवास तथा पटना के निकट दानापुर स्थित निवास को आयकर अधिकारियों, राजस्व गुप्तचर सेवा और आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के आला अधिकारियों ने सशस्त्र सीआरपी के जवानों के साथ एकबारगी चारों तरफ से घेर लिया। इन सभी जगहों पर बिल्कुल एक ही समय में छापा मारा। उस दिन खुद सत्यदेव सिंह इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और उनकी पत्नी पूजा करने देवघर गयी हुई थीं। सत्यदेव सिंह विधान परिषद के चुनाव में डा० जगन्नाथ मिश्र की प्रतिष्ठा के प्रश्न बनकर विजयी हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे ने जब सत्यदेव को धनबाद जिला बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, तो दुबे को चोट देने के लिए डा० जगन्नाथ मिश्र ने सत्यदेव को विधान परिषद में लड़ाकर जिताया था। पर बाद में सत्यदेव जगन्नाथ मिश्र से भी अलग हो गये और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 'जनमोर्चा' का गठन किया, तो वह 'जनमोर्चा' में शामिल हो गये।

सत्यदेव सिंह के काको, कतरास स्थित निवास में सघन तलाशी हुई। दानापुर स्थित निवास पर सत्यदेव के पुत्र राजीव रंजन सिंह सपत्नीक मौजूद थे। सशस्त्र जवानों सहित अधिकारियों ने पूरी तलाशी ली और इस क्रम में सत्यदेव की पत्नी के बक्से से एक लाख, दस हजार रुपए नगद बरामद हुए। पर यह संगीन छापा उस दिन अकेले सत्यदेव सिंह के यहां ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि एकसंग दिल्ली, उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल के तकरीबन ४०० वरिष्ठ अधिकारी लगभग आठ सौ की तादाद में सीआरपी की बड़ी टुकड़ी लेकर धनबाद के तमाम माफिया सरगनाओं के यहां तेजी से खाना-तलाशी ले रहे थे। सूर्यदेव सिंह के धनबाद स्थित सरायढेला के आलीशान भवन 'सिंहमैंसन' से लेकर उनके गांव गोनिया व झरिया, कतरास, पटना आदि प्रमुख ठिकानों पर तमाम अधिकारी पुलिस जवानों सहित चप्पा-चप्पा छान रहे थे। सूर्यदेव सिंह के सरायढेला स्थित मकान से दो लाख रुपए नगद पकड़े गये और करोड़ों की बेनामी संपत्ति के महत्वपूर्ण कागजात भी हाथ लगे। सूर्यदेव सिंह उस छापे के दिन दिल्ली में अपनी आंख का इलाज करवा रहे थे। वह अभी पहली फरवरी, १९८८ को धनबाद में हुए एक गोलीकांड के मामले में बंदी हैं और जेल से ही बिहार सरकार ने उन्हें आंख की चिकित्सा कराने दिल्ली भेज रखा है। छापा नौरंगदेव सिंह, सकलदेव सिंह, रामनाथ सिंह, रामचंद्र सिंह के यहां भी उसी दिन, उसी वक्त पड़ा। इन सभी के भी गांव व धनबाद से लेकर अन्य तमाम संभावित ठिकानों को सैकड़ों की तादाद में गये अधिकारियों की पलटन ने रत्ती-रत्ती छान मारा। साथ ही इन लोगों से सम्बंधित लगभग एक दर्जन अन्य लोगों के यहां भी उसी समय आकस्मिक छापा मारी हुई। नौरंगदेव सिंह के यहां से तीन लाख नगद और काफी संख्या में अवैध हथियार पकड़े गये। साथ ही नौरंगदेव के निवास से लगभग ४० लाख के फिक्स डिपोजिट के दस्तावेज जब्त किये गये। रामनाथ सिंह के यहां से भी नगद व लगभग तीस लाख के फिक्स डिपोजिट के खाते के कागजात पकड़ में आये। सकलदेव सिंह के यहां से भी नगद रुपए के अलावा लाखों की संपत्ति के कागजात पकड़ने का दावा अधिकारियों ने किया। छापे के बाद आयकर विभाग कानपुर के निदेशक टीके दास, केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय के एस नंदी व पुलिस महानिरीक्षक एसके दत्ता ने उसी शाम धनबाद के सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया। अधिकारियों ने उस भीड़ भरी प्रेस-कांफ्रेंस में बताया कि धनबाद माफिया की लगभग १५ करोड़ की सम्पत्ति का रहस्योद्घाटन इस छापे में हुआ। दिल्ली व कलकत्ता के भी कई ठिकानों पर छापे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल हुईं। यों, उस प्रेस कांफ्रेंस में अधिकारियों ने इस बात को बिल्कुल गोपनीय रखा कि किसके यहां से कितनी संपत्ति पकड़ी गयी। पर प्रेसवालों को इन अधिकारियों ने कई और विस्फोटक सूचनाएं दीं कि कैसे एक माफिया ने साठ लाख रुपए काफी हील-हुज्जत के बाद सौंपे, कि कैसे [illegible] तीन लाख रुपए एक माफिया नेता के मकान के परिसर में सूटकेस में भरकर छिपाया हुआ बरामद हुआ। साथ ही इन अधिकारियों ने यह भी सूचना दी कि तमाम माफिया नेताओं के धनबाद से लेकर दिल्ली, पटना, कलकत्ता तक के बैंक खाते सील कर दिये गये हैं।

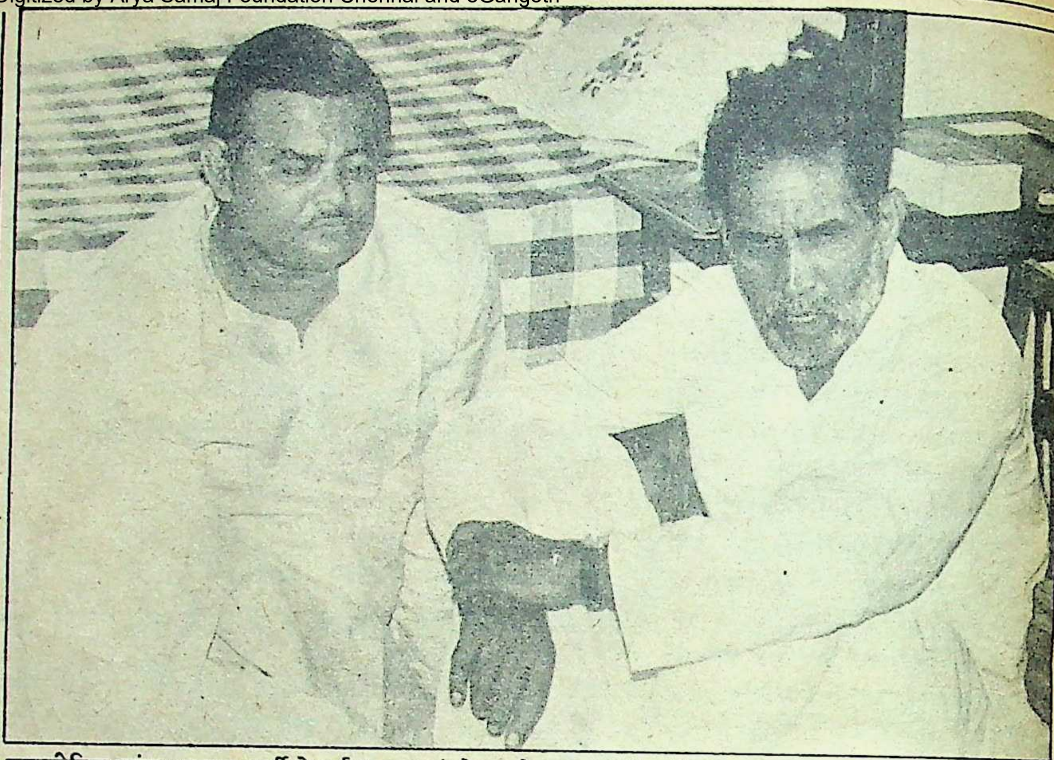

राजनीतिक पहुंच : जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर के साथ सूर्यदेव सिंह

बहरहाल, उस दिन के छापे में अवैध हथियार रखने के आरोप में नौरंगदेव सिंह को अन्य चार लोगों, प्रसिद्ध कुमार सिंह, राजेंद्र सिंह मुंदर सिंह और महेन्द्र सिंह सहित गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया गया। अन्य माफिया नेताओं का क्योंकि सिर्फ इनकमटैक्स की चोरी का मामला था, इसलिए तत्काल उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। १० जून को रिमांड पर धनबाद जेल में बंद किये गये नौरंगदेव सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी, पर वह खारिज हो गयी। पर इसी बीच १३ जून को नौरंगदेव सिंह की मां का निधन उनके औरंगाबाद जिलान्तर्गत गांव गारडीह में हो गया। लिहाजा, २३ जून की सुबह नौरंगदेव अपनी मां के श्राद्धकर्म में भाग लेने के निमित्त महज पांच दिन के लिए सशस्त्र संरक्षण में जेल से छोड़े गये। नौरंगदेव के साथ जेल में बंद उनके भतीजे प्रसिद्ध कुमार सिंह को भी नौरंगदेव के साथ जाने की अनुमति मिली। नौरंगदेव सिंह के करीबियों का कहना है कि डा० जगन्नाथ मिश्र द्वारा १२ जून को पटना में आयोजित राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के सम्मेलन में भाग लेने से रोकने के लिए ही नौरंगदेव सिंह के यहां जानबूझकर छापामारी की गयी। नौरंगदेव के निकटवर्तियों के अनुसार डा० जगन्नाथ मिश्र के उस कार्यक्रम के लिए ही नौरंगदेव ने चंदा एकत्रित किया था। उसे भी आयकरवालों ने जब्त कर लिया। दूसरी तरफ, विधान पार्षद सत्यदेव सिंह 'माया' से कहते हैं, "मेरे यहां छापा मारने का बस एक उद्देश्य था कि इलाहाबाद उपचुनाव में मैं विश्वनाथ प्रताप

सिंह की पूरी मदद नहीं कर सकूं। मैं आश्वस्त हूं कि यह छापा सिर्फ दिल्ली के इशारे पर हुआ है।'' सत्यदेव सिंह के अग्रज और धनबाद के इंका सांसद शंकरदयाल सिंह 'माया' से कहते हैं, ''यह छापा सौ फीसदी राजनीतिक है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। सत्यदेव आयकर नियमित रूप से चुकाते रहे हैं। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व वह गजरीटांड, अंगार पथरा, जीनागड़ा, कुजामा आदि आठ-दस खदानों के मालिक थे, जिसका मुआवजा उन्हें विधिवत सरकार से मिला था। सत्यदेव के पास जो कुछ भी संपत्ति है, वह सरकार की नजर से बाहर नहीं है।''

क्या खबर 'लीक' हुई ? : इस बहुर्चचित छापे को लेकर कई तरह की अटकलें अभी भी धनबाद में गर्म हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस भीषण छापे की खबर पहलें ही 'लीक' हो चुकी थी ? धनबाद के उपायुक्त मदन मोहन झा ने 'माया' को बताया कि अगर खबर खुल जाती, तो इतने बड़े पैमाने पर नौरंगदेव सिंह के यहां अवैध हथियार नहीं पकड़े जाते या फिर इतनी मोटी राशि कई माफिया नेताओं के घर से बरामद नहीं होती। लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी रकम पकड़ी गयी, वह धनबांद-माफिया के पास अपेक्षित अपार संपत्ति के हिसाब से बहुत मामूली थी। एक महत्वपूर्ण सूत्र के अनुसार इस छापे की खबर सूर्यदेव सिंह के परिजनों को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह के आप्त सचिव के हवाले से तीन-चार दिन पहले ही मिल गयी थी। यही कारण था कि सूर्यदेव के पूरे कारोबार के कर्ताधर्ता एके झा ने छापे के चार-पांच दिन पूर्व अखबारों में बयान देकर कहा था कि छापामारी की पक्की संभावना है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस छापे की सूचना थी, क्योंकि कानपुर आयकर विभाग के अधिकारी छापे की तैयारी में जुटे थे। वरना, केंद्र सरकार ने छापे की खबर को अत्यंत गुप्त रखा था।

क्या खुद वीरबहादुर सिंह ने धनबाद के अपने स्वजातीय माफियों तक छापे की खबर 'लीक' करायी? यह सवाल राजनीति के कई दिग्गज खिलाड़ियों को परेशान किये हुए है। अभी हाल में दिल्ली से जारी एक बयान में सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि धनबाद माफिया के यहां से प्राप्त धन व संभावित धन की तहकीकात और निपटारे के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। लेकिन मजदूर नेता और धनबाद के पूर्व सांसद एके राय का कहना है, ''बहुतेरे अधिकारी यहां आये, माफिया तत्वों को खतम करने की मुनादी लेकर। पर माफिया तो रह गया, वे अफसर बेचारे चले गये।''

दूसरी ओर धनबाद के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कोई आश्चर्य नहीं कि इस छापे की कार्रवाई के प्रतिक्रियास्वरूप सरकार को स्तब्ध करने के लिए धनबाद में एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो जाये? ताकि सरकार खून-खराबों से झुंझलाकर माफिया की तिजोरी का रास्ता भूल जाये।

मजदूर नेता एके राय

धन व संभावित धन की तहकीकात और निपटारे के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है लेकिन मजदूर नेता और धनबाद के पूर्व सांसद एके राय का कहना है, ''बहुतेरे अधिकारी यहां आये, माफिया तत्वों को खतम करने की मुनादी लेकर। पर माफिया तो रह गया, वे अफसर बेचारे चले गये।

धनबाद बनाम बंबई : देश के सर्वाधिक धनी शहरों में गिने जानेवाले शहर बंबई और धनबाद में बस थोड़ा सा ही फर्क है। बंबई के चरित्र में जहां आधुनिकता है, वहीं धनबाद शहर के चरित्र में 'देहातीपन' है। बंबई की धनाढ्यता कौंधती है, धनबाद की धनाढ्यता बुझी-दबी रहती है। लेकिन बंबई और धनबाद के माफिया में अनेक समानताएं भी हैं। बंबई के सभी 'डॉन' के जैसे अतीत रहे हैं, लगभग वैसा ही धनबाद माफिया का भी अतीत रहा है। अधिकांश कुली या मजदूर से कुबेर बन बैठे। धनी शहर के इन खतरनाक कुबेरों के बीच ताकत की जोर आजमाइश हर सप्ताह-महीने बंदूकों के जरिये होती रहती है। बंबई के खूंख्वार डॉन जहां व्यवसायी का बिल्ला लगाकर तमाम गोरखधंधा करते हैं, वहीं धनबाद माफिया राजनीति का बिल्ला लटकाकर सारे धंधे करता है। मजदूरों की यूनियनबाजी के बहाने खून-खराबा आम बात है। धनी शहर का हर खौफनाक कुबेर एक दूसरे के खून का प्यासा है। सूर्यदेव सिंह अभी जिस हादसे को लेकर बंदी हैं, वह इसी वर्ष की पहली फरवरी की घटना है। बिहार में बिन्देश्वरी दुबे-राज के वे अराजक दिन थे।

वह तारीख थी, १ फरवरी, १९८८। उस समय दिन के लगभग ग्यारह बजे थे। धनबाद स्थित कांग्रेस के 'राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ' के दफ्तर में लोगों की आमदरफ्त जारी थी कि अचानक नीचे पोर्टिको के पास गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। पोर्टिको में उस समय कोयलरी मजदूर संघ के संयुक्त महासचिव एसके राय की एम्बेसडर खड़ी थी और उसमें एसके राय के एक अंगरक्षक कलक्टर सिंह के अतिरिक्त बक्सर जिले के टुटुआरी गांव से आये सुरेन्द्र राय के अलावा विनय शर्मा और अनादि राय बैठे बातें कर रहे थे। सुरेन्द्र राय एक दो दिन पूर्व ही अपने गांव से आये थे, क्योंकि ८ फरवरी को होने वाले स्पेशल ट्रायल में उन्हें सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध गवाही देनी थी। सुरेन्द्र राय को एसके राय नें संवाद देकर बुलवाया था, क्योंकि १९८२ में सूर्यदेव द्वारा एसके राय पर हुए खूनी हमले के मामले की पेशी ८ फरवरी को होनी थी। एम्बेसडर में सुरेन्द्र के अलावा बैठा अनादि राय अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से इंटक कार्यालय आया था। अचानक टूट पड़े हमलावरों से एम्बेसडर में बैठे लोग हतप्रभ रह गये। गोलियों से इन सभी को बींधते हुए हमलावर कार्यालय के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़े। वहीं मजदूर संघ के वयोवृद्ध सचिव उमाकांत सिंह कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। हमलावरों ने देखते ही उन पर अंधाधुंध गोलियां दाग दीं। वह वहीं गिर गये। उस समय एसके राय अपने चेम्बर में बैठे थे। गोली की आवाज सुन पहले तो उन्हें भ्रम हुआ कि ब्लाक-दो क्षेत्र में यूनियन के चुनाव में उनकी यूनियन के देवी शर्मा की जीत हुई थी। देवी शर्मा इंटक दफ्तर में आये हुए थे। एसके राय को लगा कि दफ्तर परिसर में देवी शर्मा के उल्लसित समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं। अपने-अपने चैम्बर में बैठे अन्य मजदूर नेताओं को भी ऐसा ही शुबहा हुआ। पर हमलावर जब और नजदीक आ गये, तो एसके राय के चैम्बर के सामने बैठा उनका अंगरक्षक हरिदेव यादव तड़पकर उठ खड़ा हुआ। गोली तब तक उसकी जांघ में आ धंसी थी। फिर तो विद्युत गति से एसके राय सहित अन्य लोगों ने भी अपने-अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इधर नीचे एम्बेसडर में सुरेन्द्र राय, विनय शर्मा और अनादि राय दम तोड़ चुके थे। बुजुर्ग उमाकांत सिंह गोली से घायल अचेत गिरे थे। चंद मिनटों में सब कुछ घटित हो गया। लगभग सौ राउंड से ऊपर गोली चल चुकी थी। हमलावर जब भाग गये, तो दफ्तर के भयभीत कर्मचारी चीखने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और यूनियन दफ्तर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घायल उमाकांत सिंह को तत्काल धनबाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। दो दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गयी।

धनबाद माफिया

धनी शहर के सितारे

स्व० बीपी सिन्हा: १९५० के आसपास स्व बीपी सिन्हा ने कोयलाबहुल क्षेत्र धनबाद में श्रमिक राजनीति के जरिये अपनी गतिविधियां शुरू कीं और बाद के दो दशकों में वह इस धनी शहर के एकछत्र 'राजा' बन गये। सर्वाधिक धनी शहर के अभी जितने भी मौजूदा सितारे हैं, सब के सब इस कूटनीतिक मजदूर नेता के कारिंदे रह चुके हैं। स्व० सिन्हा की रणनीति का यह प्रतिफल था कि धनबाद में कार्यरत साधन गुप्ता जैसे ईमानदार श्रमिक नेता धुंध में खो गयें। बाहुबल और कुटिल राजनीति के दम पर इस धनी शहर की लगाम को कैसे थामा जाता है, यह अचूक फार्मूला बीपी सिन्हा का ही दिया हुआ है। आज जिस तरह सूर्यदेव का घर 'सिंह मैसन' माफिया नगरी का स्वयंभू सचिवालय माना जाता है, उसी तरह 'ह्वाइट हाउस' का भी स्व० सिन्हा के युग में एक खास रुतबा था। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सिन्हा का रुतबा और परवान चढ़ा। पर तब तक उनके लठैत भी पूरी तरह सयाने हो चुके थे। आखिरकार, माफियानगरी के इस 'आदि गुरु' की हत्या २८ मार्च, १९७८ को उन्हीं के निवास पर कर दी गयी।

राजदेव राय: १९६० से १९७० के बीच धनबाद में आतंक की प्रतिमूर्ति थे, राजदेव राय। धनबाद के लोग आज भी उनकी याद कर सिहर उठते हैं। सूर्यदेव सिंह के गुरुओं में से एक वह भी थे। पर धनबाद के नवोदित माफिया-दादाओं ने उनके गांव में ही उनकी हत्या करवा दी थी, ताकि धनबाद में उनकी हत्या का संदेह किसी पर न जाये। पर राजदेव की हत्या के बाद उनके निकटवर्त्ती बंधुओं ने राजदेव की विरासत को धनबाद में थाम लिया।

सूर्यदेव सिंह: उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के गोनिया—रानीगंज गांव के मूल निवासी सूर्यदेव का अतीत और वर्तमान क्या है; यह शायद बताने की जरूरत नहीं। दर्जनों आपराधिक मामलों में आरोपित झरिया क्षेत्र से जनता पार्टी विधायक सूर्यदेव इसी धनी शहर में निहायत फटेहाली में आये थे और रानीगंज कोक एसोसिएशन में बतौर तेलबत्ती खलासी काम करना शुरू किया था। वह अर्से तक स्व० बीपी सिन्हा के पहलवान रहे। जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर के वे सबसे चहेते हैं। सूर्यदेव के आलोचकों का कहना है कि चंद्रशेखर का कुछ व्यावसायिक कार्य गोपनीय ढंग से धनबाद में है और सूर्यदेव ही उसे 'मैनेज' करते हैं। यों पता नहीं यह बात किस हद तक सच है। सूर्यदेव के लिए ही खासतौर से धनबाद में 'माफिया' विशेषण का चलन हुआ।

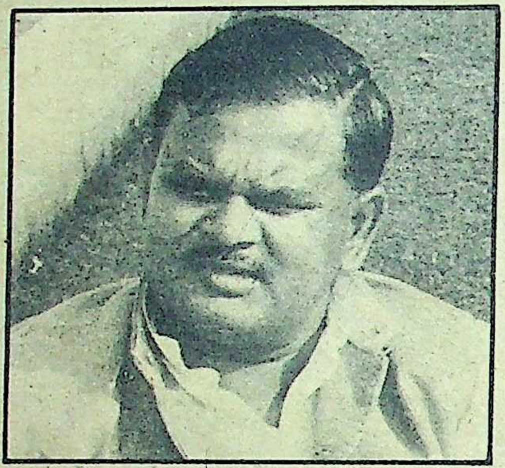

सूर्यदेव सिंह

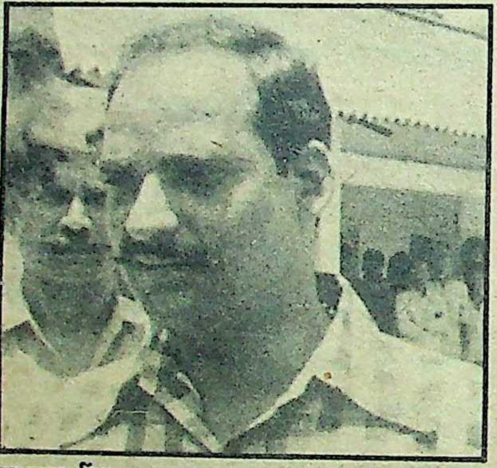

रघुनाथ सिंह

बच्चा सिंह: बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के अनुज हैं। सूर्यदेव के अधिकांश कार्यों में बच्चा सिंह की अहम भूमिका रहती है। कई संगीन मामलों में आरोपित बच्चा सिंह अनगिनत बार जेल की भी हवा खा चुके हैं।

रामधीर सिंह: सूर्यदेव के ही भाई रामधीर विगत १ फरवरी, १९८८ को धनबाद में गोलीकांड के दौरान हुए हत्याकांड के सिलसिले में धारा ३०२, ३०७, ३२४, ४५२ आदि के तहत अभी धनबाद जेल में बंद हैं। ११ जुलाई, १९७९ का भी एक केस धारा ३०२ के तहत उन पर चल रहा है।

नौरंगदेव सिंह: नौरंगदेव सिंह धनबाद की एक प्रमुख हस्ती हैं और ९ जून के छापे में गिरफ्तार होने के बाद तो और भी सुर्खियों में हैं। कई संगीन मामलों में उलझे नौरंगदेव की सूर्यदेव सिंह के साथ कई जगह साझा ठेकेदारी भी चलने की बात कही जाती है। कलकत्ता की एक अंकेक्षण कंपनी के शाश्वत सुंदरदास हत्याकांड को लेकर नौरंगदेव सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे।

रामचंद्र सिंह: नौरंगदेव सिंह के भाई रामचंद्र सिंह भी सूर्यदेव के भाई बच्चा सिंह की प्रतिमूर्ति हैं। दास-हत्याकांड में रामचंद्र का नाम भी गूंजा था। रामचंद्र धनबाद में बालू के अव्वल ठेकेदार रहे हैं।

सकलदेव सिंह: बिहार के छपरा जिले के गरखा थाने के अढ़ूपुर गांव के मूल निवासी सकलदेव सिंह भी धनबाद की एक बड़ी हस्ती हैं। सकलदेव की महिमा धनबाद के अन्य 'देवों' से रत्ती भर भी कम नहीं है। सकलदेव अभी जनता पार्टी में हैं और १९८५ के चुनाव में वह सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र से लोकदल नेता लालू यादव के खिलाफ चुनाव में भी खड़े हुए थे। सकलदेव उस चुनाव में तो हारे ही, साथ ही उनके अपने सगे भाई नागेन्द्र सिंह की भी हत्या चुनाव के दौरान हो गयी। सकलदेव के लोगों को आज भी संदेह है कि नागेन्द्र सिंह की हत्या धनबाद के उनके दुश्मनों ने ही की। सकलदेव सिंह के एक अनुज विनोद सिंह संप्रति धनबाद जेल में गजलीटांड कोयलरी में हुए गोलीकांड व अन्य मामलों के तहत बंद है।

रामनाथ सिंह: धनबाद के इंका सांसद शंकर दयाल सिंह के रिश्तेदार रामनाथ भी एक बड़ी हस्ती हैं। कोयले के चूरे के कारोबार में रामनाथ ने अच्छी कमाई की। राजनीतिक ताकत और बाजुओं में जोर हो, तो यह धनी शहर उसका गुलाम हो जाता है। रामनाथ इस गुर को अच्छी तरह समझते हैं।

रघुनाथ सिंह: धनबाद के नवोदित डॉन रघुनाथ सिंह अभी धनबाद जेल में विगत एक माह से कैद हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के मूल निवासी रघुनाथ पहले फौज में कोई छोटी नौकरी करते थे। पर कुछ कारणों से वह फौज से फरार हो गये। रघुनाथ ने अर्से तक सूर्यदेव सिंह की लठैती की। स्व० बीपी सिन्हा की हत्या में रघुनाथ की प्रमुख भूमिका थी। रघुनाथ गुरुबचन सिंह हत्याकांड के सिलसिले में भी काफी सुर्खियों में आये। हत्या, रंगदारी आदि से संबंधित दर्जनों मामले रघुनाथ पर चल रहे हैं। बीच में रघुनाथ का अपने पुराने मालिक सूर्यदेव सिंह से तनाव हो गया था। पर इधर जेल में रघुनाथ और सूर्यदेव के बीच संधि की चर्चा जोरों पर है। रघुनाथ अचूक निशानेबाज हैं। धनबाद के कुछ लोग कहते हैं कि निशानेबाजी में वह 'पृथ्वीराज चौहान' हैं जो महज आवाज सुनकर गोली से किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। पर, धनबाद थाने में दरोगा रहे आरके वर्मा ही इकलौते भाग्यशाली हैं जो रघुनाथ के हाथों सिर में गोली लगने के बावजूद जिंदा हैं।

—विकास कुमार झा

१ फरवरी के उस हादसे के बाद धनबाद पुलिस ने बड़ी बेसब्री से सूर्यदेव सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। पर सूर्यदेव पुलिस को छापे में हाथ नहीं लगे, लेकिन उन्होंने ६ फरवरी की दोपहर अचानक धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जब तक एसके राय के लोगों को आत्मसमर्पण की खबर मिलती, तब तक चंद मिनटों के भीतर सूर्यदेव धनबाद जेल के भीतर बंद किये जा चुके थे। इसके पूर्व ३ फरवरी को इस हादसे के विरोध में धनबाद पूरा बंद रहा था, यहां तक कि कोयला खदानें भी ठप्प रहीं।

माफिया का खूनी खेल : धनी शहर की यही आचारसंहिता और चलन है। ९ जनवरी, १९७९ को पहले भी एसके राय पर ऐसा ही खूनी हमला हुआ था। लेकिन उन दिनों वह कांग्रेस में नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी में थे। उस हमले में राय तो बच गये थे, पर उनके संग चल रहे तीन लोग जान से हाथ धो बैठे थे। १९७९ के उस जनवरी माह में लगातार पांच हत्याएं हुई थीं। पहली हत्या ३ जनवरी, १९७९ की सुबह साढ़े नौ बजे भागाबांध खदान के भुगतान काउंटर पर नौजवान मजदूर श्याम नारायण राय की हुई। सरेआम हमलावरों ने उसे खींच लिया और उससे पूछा कि वह 'जनता मजदूर संघ' को चंदा देने से इनकार क्यों करता है और फिर उसे वहीं गोली मार दी गयी। जब पुलिस थोड़ी देर बाद वहां पहुंची, तो मारे डर के किसी मजदूर की जुबान तक नहीं हिली। इसी क्रम में तीन-चार हत्याएं और हुईं।

धनबाद में माफिया शैली की राजनीति के निर्माता मजदूर नेता स्व० बीपी सिन्हा थे। धनबाद का हर आला सरकारी अधिकारी उनके सामने सिजदा करता था। पर बाद में उनके लठैत शिष्यों ने ही उनकी हत्या कर दी। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद खदानों में कार्यरत सूर्यदेव सिंह जैसे पहलवान ठेकेदार बन गये। फिर ठेकेदारी पर 'कब्जे' को लेकर खूनी संघर्ष तीव्र होता गया।

बीपी सिन्हा की हत्या के बाद सूर्यदेव सिंह इस धनी शहर के बेताज बादशाह बने। झरिया से वह जनता पार्टी टिकट पर तो जीतें ही आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने एक-एक कर इंटक की यूनियनों को अपने जनता मजदूर संघ में विलीन करना शुरू किया। धीरे-धीरे सूर्यदेव की पटरी पकड़कर कई और शूरमा इस धनी शहर में अवतरित हुए। १९७४ में सूर्यदेव ने बोर्रागढ़ और कुस्तौर खदानों से बीपी सिन्हा समर्थकों को बुरी तरह खदेड़ दिया। १९७७ के अक्तूबर माह से भूरीडीह खदान में तो इंटक और सूर्यदेव के जनता मजदूर संघ के बीच जमकर संघर्ष हुआ।

जातीय समीकरण : दरअसल, धनबाद में भूमिहारों का राजपूतों से तनाव स्व० बीपी सिन्हा की हत्या के बाद से ही है। एक खेमा यहां बाहुबली राजपूतों का है, तो वहीं दूसरा खेमा कूटनीतिक भूमिहारों का। स्व० सिन्हा जाति के भूमिहार थे और अपना दबदबा कायम करने के लिए उन्होंने ज्यादातर जिन लठैतों का सहारा लिया, वे सब जाति के राजपूत थे। धनबाद की राजनीति में बीपी सिन्हा का नेतृत्व जब तक कायम रहा, जाहिर तौर पर भूमिहारों की तूती बोलती रही। पर धीरे-धीरे राजपूतों को लगा कि उनकी ताकत से भूमिहार जाति के लोग ही भला क्यों लाभ अर्जित करते रहें। सो, आक्रोश ने तभी से जड़ जमाना शुरू कर दिया। सिन्हा के राजपूत लठैत दोयम दर्जे का व्यवहार अधिक दिनों तक सहन करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी बीच सिन्हा के ही लोगों द्वारा चंद राजपूतों की हत्या हो गयी। नतीजतन, राजपूतों का घायल गुस्सा सिन्हा की मौत का कारण बन गया। सिन्हा की हत्या ने धनबाद में काबिज भूमिहार लॉबी को बुरी तरह झकझोर दिया। यों उन दिनों भूमिहार नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी से एसके राय भी नये-नये उभरे थे। पर एसके राय में बीपी सिन्हावाला करिश्मा एक पाई भी नहीं था। इसके अलावा अर्से तक स्व० राम नारायण शर्मा इंटक (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस) के महामंत्री रहे और धनबाद की राजनीति में जद्दोजहद करते रहे। पर स्व० शर्मा भी स्व० बीपी सिन्हा के पर्याय नहीं बन सके।

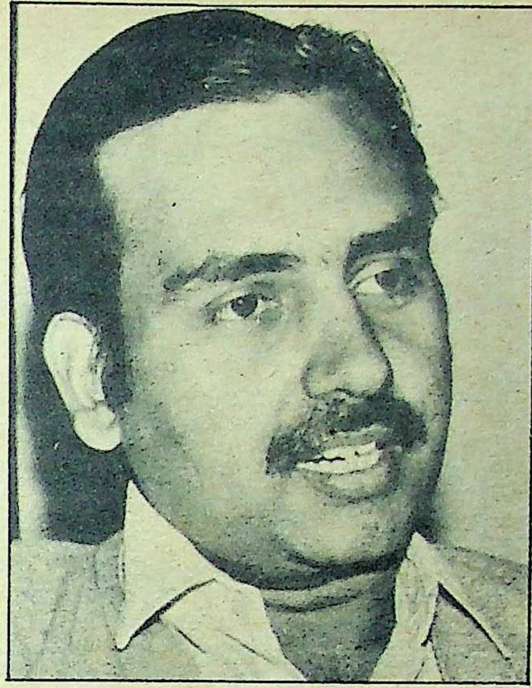

छापे फिर पड़ेंगे : मदन मोहन झा

धनबाद के उपायुक्त मदन मोहन झा ने 'माया' को बताया कि अगर खबर खुल जाती, तो इतने बड़े पैमाने पर नौरंग देव सिंह के यहां अवैध हथियार न पकड़े जाते। लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी रकम पकड़ी गयी वह धनबाद-माफिया के पास अपेक्षित अपार संपत्ति के हिसाब से बहुत मामूली थी।

सूर्यदेव से अंतरंगता : विधायक एसपी राय

बहरहाल, धीरे-धीरे भूमिहार लॉबी लगभग नेतृत्वविहीन हो गयी। सो अपनी दुश्मन राजपूत लॉबी से टकराने की शक्ति अर्जित करने के लिए भूमिहारों ने ब्राह्मण लॉबी से गंठबंधन किया। उस समय से ब्राह्मण लॉबी का नेतृत्व कर रहे थे, बिन्देश्वरी दुबे। दुबे ने भूमिहार लॉबी के लिए एक नया कैडर जरूर तैयार कर दिया। इनमें धनबाद के मौजूदा इंका विधायक एसपी राय जैसे कई लोग थे। दुबे ने ही एसपी राय को धनबाद विधान सभा क्षेत्र से इंका का टिकट दिलाया। पर अभी राय दुबे के साथ न होकर डा० जगन्नाथ मिश्र के समानांतर इंटक के कर्त्ताधर्त्ता हैं। एसपी राय की वफादारी टूटने से नाराज दुबे ने अर्से से कम्युनिस्ट पार्टी में रहे पूर्व विधायक एसके राय को कांग्रेस में आननफानन में प्रवेश दिलाया और साथ ही इंटक की राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ में प्रमुख पदाधिकार भी दिया। पर इधर फिर एसके राय भी दुबे के खिलाफ हो गये हैं, क्योंकि इंटक की नयी कमेटी के पनुर्गठन में राय को दुबे से यह आशा थी कि दुबे उन्हें कोई प्रमुख पद देंगे। पर दुबे ने पहले तो इंटक कमेटी में तमाम ब्राह्मणों को भर दिया और बाद में खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पर दुबे से भूमिहार अभी भी नाराज चल रहे हैं। वैसे शुरू के दिनों में बिन्देश्वरी दुबे ने गोह से विधायक डीके शर्मा और सिद्धेश्वर सिंह आदि को जब इंटक में प्रमुख पदाधिकारी बना दिया था, तो भूमिहार लॉबी दुबे पर पूरा भरोसा करने लगी थी। पर अब भूमिहार लॉबी का कहना है कि दुबे ने भी उन सभी का इस्तेमाल कर बस ब्राह्मण राजनीति के स्वार्थ का हितसाधन किया।

बहरहाल, गुजरे वर्षों में दुबे के कारण इंटक में भूमिहार लॉबी को सम्मानित देख राजपूत क्षुब्ध थे। लिहाजा, धनबाद के इंका सांसद शंकरदयाल सिंह उनके विधान पार्षद अनुज सत्यदेव सिंह, हाल

खतरा मुझे भी है: राज्यमंत्री ओपी लाल

के छापे में गिरफ्तार नौरंगदेव सिंह सरीखे राजपूत अलंबरदार काफी आहत थे। इस तरह धनबाद की राजनीति में भीतर और बाहर राजपूत-भूमिहार एक दूसरे के प्रति तीव्रता से आक्रामक होते गये। आपसी घृणा का यह अंतहीन सिलसिला आनेवाले कई दशकों तक धनबाद को तबाह भी करता रहेगा। भूमिहार आज तक इस बात को अपने दिल से धो नहीं पाये हैं कि इस सर्वाधिक धनी शहर पर कायम उनकी हुकूमत के भंजक राजपूत ही हैं।

इधर सूर्यदेव सिंह झरिया से जनतापार्टी के विधायक हो गये और अपने जनता मजदूर संघ के ज़रिये उन्होंने कोयला खदानों पर दबदबा कायम करना शुरू किया, तो राजपूतों का हौसला बढ़ा। सूर्यदेव ने भी अपनी जाति के कई पहलवानों का राजनीतिक परिष्कार कर इस धनी शहर में पैसे का खेल खेलने के लिए उतारा। नौरंगदेव सिंह, रामचंद्र सिंह, सकलदेव सिंह और यहां तककि रघुनाथ सिंह का भी परोक्ष-प्रत्यक्ष पृष्ठपोषण किया। बाहुबल के मामले में राजपूत लॉबी मजबूत थी ही। इसमें भूमिहार काफी पीछे रह गये।

कौन है, इस धनी शहर का राजा? बेशक अभी सूर्यदेव सिंह और आनेवाले दिनों के लिए कई राजपूत उत्तराधिकारी तैयार हो चुके या हो रहे हैं। पर भूमिहार लॉबी धनबाद में अपनी भावी पीढ़ी को भी समर्थ करने में पिछड़ी हुई है। हां, एसपी राय ने राजपूत-भूमिहार लॉबी की रंजिश को लांघने की जुर्रत की और उस सूर्यदेव सिंह से आत्मीय संबंध बनाये जिससे तमाम भूमिहार नफरत करते हैं। सो भूमिहार लॉबी विधायक एसपी राय को विश्वासपात्र नहीं मानती।

आपसी टकराव: राजपूत लॉबी में भी आपसी टकराव कम नहीं है। मसलन, सूर्यदेव सिंह और धनबाद के एक अन्य राजपूत बाहुबली सकलदेव सिंह में बेहद कटु संबंध हैं। यों सकलदेव भी जनता पार्टी में हैं और १९८२ तक सूर्यदेव के साथ ही थे। सकलदेव सिंह सूर्यदेव सिंह के 'जनता मजदूर संघ' के समानांतर मजदूर संगठन 'बिहार जनता खान मजदूर संघ' चलाते हैं। १९८६ तक रघुनाथ सिंह सकलदेव के अंगरक्षक थे। १९८३ में एक बार सकलदेव सिंह व रघुनाथ सिंह को मार गिराने के लिए धनबाद के सिजुआ मोड़ स्थित सकलदेव के निवास पर सूर्यदेव सिंह के लोगों ने लगातार ढाई घंटे तक फायरिंग की थी। सकलदेव धनबाद के इंका सांसद शंकरदयाल सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं, पर २६ दिसंबर, १९७८ को सकलदेव के पिता मुखराम सिंह की हत्या में शंकरदयाल सिंह के विधान पार्षद भाई सत्यदेव सिंह का भी नाम आया। उसी दिन से शंकरदयाल सिंह व सत्यदेव सिंह से भी सकलदेव के कटुतम संबंध हैं। एक बार सिताबदियारा में जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शंकरदयाल सिंह, सूर्यदेव सिंह व सकलदेव सिंह में सुलह कराने की कोशिश की थी पर उस समझौतावार्ता के दौरान स्थिति इतनी संगीन हो गयी कि बात बन नहीं सकी। यह तनाव आज भी बरकरार है।

हत्या का भय: बहरहाल, इस धनी शहर के आकाओं को कई लाभ हैं, तो कई खतरे भी। धनबाद के जितने भाग्य-विधाता हैं, सबके जीवन पर कभी-न-कभी घातक हमला हो चुका है। भूतपूर्व खान एवं भूतत्व राज्यमंत्री ओम प्रकाश लाल धनबाद जिले से ही विधायक हैं। लाल पर १९८४ में जानलेवा हमला हुआ था। लाल को मंत्री बनाने के पीछे भी उस समय बिन्देश्वरी दुबे-राज में यही तर्क दिया गया था कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए मंत्री बनने से स्वत: इनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुलभ हो जायेगी। सचमुच यह इस धनी शहर की विद्रूपता ही तो है, जहां जान की रक्षा के लिए मंत्री बनना जरूरी होता है। धनबाद के इंका विधायक एसपी राय के मुताबिक १९८६ में उन पर भी हमला हुआ था। उनके घर पर गोली चली थी। हालांकि एसपी राय की जान को ज्यादा खतरा नहीं दीखता, क्योंकि अभी सूर्यदेव सिंह उनपर मेहरबान हैं। धनबाद में डा० जगन्नाथ मिश्र की राजनीति करने जब एसपी राय कूदे थे, तो उस समय धनबाद के इंका सांसद शंकरदयाल सिंह और उनके अनुज सत्यदेव सिंह ने भी जगन्नाथ खेमे का खुला साथ दिया था और धनबाद में एसपी राय, शंकरदयाल सिंह और सत्यदेव सिंह का नया समीकरण उभरा था। इस समीकरण के परोक्ष सहयोगी सूर्यदेव सिंह भी थे। पर बाद में शंकरदयाल सिंह, सत्यदेव सिंह की एसपी राय से इसलिए ठन गयी कि एसपी राय का ज्यादा झुकाव सूर्यदेव की तरफ क्यों है। इस लड़ाई में शंकर-सत्यदेव बंधु एसपी राय की वजह से बाद में डा० जगन्नाथ मिश्र से भी नाराज होकर अलग हो गये।

बम्बई के खूंख्वार डान जहां व्यवसायी का बिल्ला लगाकर तमाम गोरखधंधा करते हैं, वहीं धनबाद माफिया राजनीति का बिल्ला लटका कर सारे धंधे करता है। मजदूरों की यूनियनबाजी के बहाने खून खराबा आम बात है। इस धनी शहर का हर खौफनाक कुबेर एक दूसरे के खून का प्यासा है।

पहली फरवरी के हादसे में मौत: उमाकांत सिंह

बहरहाल, धनी शहर के इन हुक्मरानों के रिश्तों का भी अजीब तानाबाना है। कभी जानी दुश्मन अंतरंग हो जाते हैं तो कभी गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बंबई के 'डॉन' एक उसूल के साथ अपराध करते हैं और वहां उसूल जब कोई तोड़ देता है, तो वह असहनीय होता है। पर धनबाद के माफिया ईमान व उसूल से कोसों दूर होते हैं। यहां भरोसा कायम कर धोखा देना, बगल में बिठाकर हत्या करवा देना आम बात है।

सचमुच धन ही धनबाद का दुर्भाग्य है। धनबाद में धन के आंकड़े क्या हैं? बस उतना ही जितने यहां के माफिया मजदूर नेता की चल-अचल संपत्ति और धरती में दबा बेशुमार सहस्त्र अरब का कोयला है। इसके अलावा धनबाद में किसी के पास धन नहीं। सबके सब गरीबी से बेतरह टूटे हुए हैं। अब तो दिल्ली ने खुद धनबाद की लगाम थाम ली है। पर देखना यह है कि धनबाद माफिया इस लगाम से सहमता है या लगाम तोड़ बैठता है।

—विकास कुमार झा

छाया: प्रभाकर

Mastaba
2 in one
a perfect blend of
pan masala and tobacco
BLISS/DEL

मस्ती का नाम है...

मस्ताबा

टू इन वन

गुटका

1.5 ग्राम, 3 ग्राम तथा
5 ग्राम के पाउच में उपलब्ध हैं।

मार्केटिंग एजेन्टस्
धर्मपाल सत्यपाल
बी–18, सैक्टर–3, नौएडा (यू० पी०)

वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

अधिकृत विक्रेताः **मेरठः** में. एसजी एजेन्सीज, **आगराः** में. आगरा एजेन्सीज़, **अलीगढ़ः** में. मोहन ट्रेडर्स, **अल्मोडाः** में. हरी किशन कपूर **बदायूँः** में. रामलाल रामनिवास, **बदायूँः** में. महावीर प्रसाद आनन्द प्रकाश, **चन्दौसीः** में. सुनिल कुमार मनोज कुमार, **बरेलीः** में. कृष्णा इन्टर प्राइजेज, **एटाः** में. सिंघल जर्दा हाउस, **फिरोजाबादः** में. पाण्डे राजा राम गुलाब चन्द जैन एण्ड सन्स, **हल्द्वानीः** में. कपूर टोबैको स्टोर, **हाथरसः** में. जे.सी. टोबैको एजन्सीज, **कासगंजः** में. त्रिवेणी बिजनेस कम्बाइन, **मथुराः** में. जैन एजेन्सीज **कानपुरः** में. बाजपेयी जनरल स्टोर, **पटनाः** में. एस.के. ट्रेडर्स, में. डी. लाल एण्ड सन्स (एजेन्सीज), **गोरखपुरः** में. बल्देव राम मोहन लाल, **अहमदाबादः** में. रूचि इन्टर प्राइजेज, **जैपुरः** में. शिवनाथ प्रसाद चौरसिया, **जोधपुरः** में. नरायन दास भाग चन्द, **कोटाः** में. अकुंर सुपारी स्टोर, **उदयपुरः** में. रतनलाल भंवर लाल जैन, **राजकोटः** में. दामजी राघव जी एण्ड कं., **सिलीगुड़ीः** में. बन्सल एजेन्सी, **सूरतः** में. शाह भरत कुमार अमृत लाल, **सुरेन्द्र नगरः** में. चिमन लाल भगवान जी एण्ड कं., **भावनगरः** में. साधना एजेन्सी, **धोराजीः** में. इब्राहिम ए. लतीफ, **जूनागढ़ः** में. मोहन लाल केशव दास एण्ड कं., **बरोड़ाः** में. हिन्द स्टोर्स, **हनुमानगढ़ः** में. भारतीय भुजिया मिष्ठान भण्डार **दुबईः** में. मधुर स्टोर्स,

मधु लिमये

राजनीति करवट ले रही है

निःसंदेह हाल में हुए उपचुनावों के नतीजे राजीव गांधी के लिए गंभीर चेतावनी हैं। साथ ही विपक्ष के लिए यह परिणाम एक आशा की किरण भी है। राजीव गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया समाचार पत्रों में छपी है, उससे नहीं लगता है कि इन नतीजों पर उन्होंने गहराई में जाकर विचार किया है। उनकी प्रतिक्रिया आत्मसंतुष्टि की परिचायक है। राजीव के विचारों में वैसे भी कभी गहराई रही ही नहीं है। वह सतही तौर पर सोचते हैं। स्थिति को और प्रश्नों को समझने की कूबत उनमें है ही नहीं। अतः इस गंभीर हार के बाद भी वह जगेंगे और नीति कार्यक्रम के स्तर पर या कांग्रेस संगठन के स्तर पर वह कोई बुनियादी परिवर्तन लायेंगे, इसकी कम ही आशा दिखायी देती है। राजीव गांधी ने कहा, "चुनाव परिणामों से मुझे प्रसन्नता है और इससे स्पष्ट होता है कि मतदाताओं का अभी भी कांग्रेस में विश्वास है।" इस निष्कर्ष पर वह किस आधार पर पहुंचे हैं, यह कहना मुश्किल है। लगता है, बार-बार हवाई जहाज से प्रवास करने के कारण उनका मन आसमान में उड़ता रहता है, वह कभी धरातल पर आता ही नहीं। अन्यथा इस तरह का छिछला वक्तव्य चुनाव नतीजों पर वह नहीं देते।

१९८४-८५ की अभूतपूर्व जीत के बाद राजीव गांधी की जनप्रियता में वृद्धि होने के बजाय वह लगातार गिरती जा रही है। लोकसभा में उनकी जीत का कारण उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या थी, न कि राजीव गांधी की योग्यता और जनप्रियता। उसके पश्चात राज्य विधान सभाओं के जितने महत्वपूर्ण चुनाव हुए, उन सब में उनकी हार हुई। पंजाब, असम, आंध्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा ये सब पराजय की मालिका हैं। हां! मेघालय, त्रिपुरा आदि पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्यों में उन्हें सफलता जरूर मिली है। पर राष्ट्रीय दृष्टि से इस सफलता का कोई खास मतलब नहीं है। इसी पूर्वांचल के इलाके में, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिजोरम में लालडेंगा ने कांग्रेस को बुरी तरह परास्त किया। अपनी शानदार जीत के बाद १९८५ में राजीव गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी महोत्सव धूमधाम से मनाया। लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि इस सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था को तहस-नहस करने का 'श्रेय' भी राजीव गांधी को ही मिलने वाला है। १९८० के बाद इंदिरा गांधी और विशेष कर, राजीव गांधी ने अपने ही दल के साथ जो रुख अपनाया है, उससे तो यही स्पष्ट होता है। जिस तरह प्रांतीय स्तर के नेताओं को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, मुख्य मंत्रियों के रास्ते में रोड़े अटकाये जा रहे हैं, आवश्यक और अनिवार्य सत्तांतर रोका गया है; उससे यही अनुमान किया जा सकता है कि अपने राजनीतिक गढ़ों को अपने ही हाथ से नेहरू-गांधी परिवार के उत्तराधिकारी नष्ट करना चाहते हैं।

मुझे लगता है कि राजीव गांधी संघ राज्य के ढांचे को समाप्त कर देश में केंद्रानुगामी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अन्यथा विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित करने की आवश्यकता उन्हें क्यों महसूस होने लगी है? संविधान में राज्यपाल को राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों का दर्जा दिया गया है। वास्तव में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उन्हें अपनी बुद्धि से पालन करना चाहिए। पर विगत ३५ वर्षों में केंद्रीय सरकार के एजेंटों के रूप में उन्होंने काम किया। केंद्र की जनता सरकार का भी यही रुख रहा। जिस ढंग से देवराज अर्स को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल के द्वारा बरखास्त किया गया, उस से यही सिद्ध होता है। राजीव गांधी तो खुलकर कहते हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट हैं। अब केंद्रीय काबीना के सचिव ने एक नया और अनोखा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के मुख्य सचिव केंद्र और राज्यों के बीच में एक कड़ी हैं और इसको दृष्टिगत रखकर उन्हें काम करना चाहिए। उपरोक्त घटनाओं का यह साफ मतलब है कि जिला मजिस्ट्रेटों को ही नहीं, बल्कि राज्य के मुख्य सचिवों को अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों के प्रति वफादार नहीं रहना है। उन्हें अपनी निष्ठा को केंद्र और राजीव गांधी के पदों में समर्पित करना है।

पुरानी राजनीतिक संस्था को तहस-नहस करने का 'श्रेय' भी राजीव गांधी को ही मिलने वाला है। १९८० के बाद इंदिरा गांधी और विशेषकर, राजीव गांधी ने अपने ही दल के साथ जो रुख अपनाया है, उससे तो यही स्पष्ट होता है।

मैंने प्रारंभ में ही कहा कि उपचुनावों के नतीजे विपक्ष के लिए आशादायी हैं। क्या विपक्ष के नेता इससे सही निष्कर्ष निकाल कर सहयोग की ओर आगे बढ़ेंगे? और विपक्ष की एकता का कोई ढांचा बनायेंगे? पिछले अप्रैल से अजीत लोकदल और जनता पार्टी के विलीनीकरण को लेकर जो वितंडावाद बीजू, हेगड़े, दंडवते आदि के द्वारा खड़ा किया गया था, वह कोई दूरदृष्टि का परिचायक नहीं था। साथ ही रामकृष्ण हेगड़े द्वारा कर्नाटक में जो संकीर्णता और गुटबंदी का प्रदर्शन किया जा रहा है, वह भी अकलमंदी की निशानी नहीं है। भारत के अंग्रेजी समाचार पत्र उच्चवर्णीय और उच्चवर्गीय लोगों के हाथ में हैं। उनकी राय में ब्राह्मण नेता हमेशा निःस्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होते हैं और जाट, वक्कलिगा, कुर्मी, यादव, कम्मा, रेड्डी हमेशा सत्तालोलुप होते हैं। मोरारजी भाई के द्वारा चरणसिंह, देवीलाल, रामनरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर को हटाया जाना सर्वथा उचित था। उन्हें लगता है कि हेगड़े के द्वारा देवेगौड़ा को बार-बार जलील किया जाना कि वह कांग्रेस से मिले हुए हैं, पूर्णतया समर्थनीय है। मुझ जैसे आदमी को यह दोहरा मापदंड अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि देवेगौड़ा और उनका एक मित्र होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस से उनकी प्रतिभा कलंकित होगी और नेतृत्व देने की उनकी क्षमता के बारे में समझदार लोगों में संदेह उत्पन्न होगा।

गुजरात और राजस्थान के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। गुजरात में जनता पार्टी और भाजपा ने परस्पर सद्भाव से काम लिया। उससे विपक्ष को लाभ हुआ। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही राजस्थान की भाजपा भैरों सिंह बनाम चतुर्वेदी विवाद में उलझी हुई है। पाली और खेतड़ी का उन्हें और लोकदल को बंटवारा कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केदारनाथ साहनी, शर्मा आदि भाजपा के सचिव हर दिन बयान दे रहे थे कि पिछले पाली लोकसभा चुनाव में लोकदल को सिर्फ आठ हजार वोट मिले थे। इस उपनिर्वाचन में लोकदल को ७३ हजार वोट मिले। तो क्या अब साहनी-शर्मा मानेंगे कि लोकदल की लोकप्रियता दस गुनी बढ़ी है? इस तरह के वक्तव्य बचकाना हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों से यह स्पष्ट होता है कि वहां भाजपा अपने बलबूते पर कांग्रेस को हराने में पूर्णतया असमर्थ है, जैसे गुजरात में जनता

पार्टी भी अकेले कांग्रेस को नहीं परास्त कर सकती। अरुण नेहरू विपक्षी दलों के बीच राज्यों को बांटने की बात करते हैं, मेरी राय में यह बात बेमानी है। आंध्र में तेलुगू देशम, हरियाणा में लोकदल, असम में असम गण परिषद की जो स्थिति है, वह हरगिज भाजपा की दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं है। अतः इन राज्यों की सीटों का बंटवारा कर संयुक्त चुनाव अभियान चलाने से ही अच्छे नतीजे निकलेंगे। आंध्र, हरियाणा तथा असम में भी यह आवश्यक है। राजस्थान में भाजपा के पास भैरों सिंह जैसे जनप्रिय नेता होते हुए भी उनमें और चतुर्वेदी ग्रुप में लगातार खींचातानी चलती रहती है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भाजपा के पास एक भी जनप्रिय नेता नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा के तानाशाह नेता कुशाभाऊ ठाकरे को जनता बिलकुल नहीं चाहती। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बिलकुल अपनी जेब में रखा है। मार्क्सवादी पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी नये नेतृत्व का विकास बरसों से रुक गया है। अडवाणीजी जायेंगे—अटलजी आयेंगे। अटलजी हटेंगे, अडवाणीजी पुनः सत्ता में आयेंगे। अडवाणीजी हमेशा विश्वसनीयता की बात करते हैं। कहते हैं, एकता से विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो नेता जनता के चुनाव लड़ने से कतराते हैं, बार-बार फर्जी तौर पर अपने निवास स्थान बदलकर, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश से राज्य-सभा में आना जीवन-मरण का सवाल मानते हैं, वे विश्वसनीयता और नैतिकता की बात करें और कहें कि यह परिवार घूसखोर है, अजीब लगता है। पर क्या रामकृष्ण हेगड़े, उनके पुत्र और दामाद दूध के धुले हुए हैं?

युगांतरकारी घटना: मेरी राय में हाल में हुए उपनिर्वाचन को एक युगांतरकारी घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। देवी लाल, मुलायम सिंह और अजीत सिंह ने इन उपनिर्वाचनों में समझदारी से काम लिया। यह संतोष की बात थी कि हरियाणा की पुरानी गलती को अजीत सिंह ने नहीं दोहराया। देवीलाल ने भी छपरौली में उम्मीदवार न खड़ा कराकर अच्छा काम किया। टांडा (फैजाबाद) की सीट के बारे में भी अजीत और मुलायम सिंह ने सूझ-बूझ से काम लिया। नतीजा हुआ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हुआ।

यहां विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कुछ कहना अनुचित नहीं होगा। उनकी जीत पर मुझे बड़ी खुशी है। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। पर अनावश्यक घोषणा, अनावश्यक संकल्प और अनावश्यक अंतरात्मा की आवाजें आदि के पाखंड से वह बचें। उन्होंने स्वयं मुझसे दो बार कहा था कि वह कदापि उपनिर्वाचन नहीं लड़ेंगे। इलाहाबाद से भूरे लाल को लड़ायेंगे। आगे वह कहने लगे कि यदि कांग्रेस इलाहाबाद से दुबारा अमिताभ बच्चन को खड़ा करेगी, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, अन्यथा बिलकुल नहीं। अपने इस वचन को उन्होंने २५ दिन और २५ बार दोहराया। मुझे बताया गया है कि अंतिम दिन टीवी पर भी उन्होंने यही कहा। इन वक्तव्यों का क्या औचित्य था? जहां तक विपक्ष का सवाल था बच्चन के लड़ जाने पर या अन्यथा, हर हालत में उनका समर्थन करने के लिए तैयार था। अमिताभ बच्चन कौन चीज हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह को और विपक्ष को अमिताभ बच्चन का विकल्प देना है या राजीव गांधी का और कांग्रेस का? आइंदा इस तरह की बयानबाजी इस तरह का ढोंग-धतूरा विश्वनाथ प्रताप सिंह न करें। हास्यापद्र है। अटलजी बड़े वक्ता हैं। उनमें दूसरे गुण भी हैं। पर संसद के बाहर रहने से उनकी 'जल बिन मीन' जैसी स्थिति हो जाती है। १९६२ में वह लोकसभा का चुनाव हार गये। लेकिन फौरन पीछे के दरवाजे से राज्यसभा में घुसे। १९८४ में हारने के पश्चात् अटलजी चैन खो बैठे। फिर विगत साल अवसर प्राप्त होते ही वह चुपचाप राज्य सभा में दाखिल हो गये। चंद्रशेखर में बहुत सारी बुराइयां हैं। नौ साल अपना पद न छोड़कर उन्होंने पदलोलुपता का घृणास्पद परिचय दिया। लेकिन एक बात को लेकर उनकी मैं जरूर इज्जत करता हूं। १९८६-८८ में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आ सकते थे। फर्जी तौर पर निवास स्थान बदलने की भी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। पर उन्होंने राज्यसभा में जाना तौहीन समझा, इसलिए मैं उनकी जरूर प्रशंसा करता हूं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक वर्ष आंदोलन और संघर्ष की चर्चा में ही बिता दिया। अब समय आया है, प्रत्यक्ष कर्म का। व्यापक जन आंदोलन के बिना समाज का अराजनीतिक हिस्सा आंदोलित नहीं होगा।

इस समय विपक्ष को कम-से-कम संघीय संगठन की रचना करनी चाहिए। जैसे एनटी रामाराव इधर कह रहे हैं कि उन्हें एक समान पार्लियामेंटरी बोर्ड बनाना चाहिए, जो उम्मीदवारों का चयन करे। अगर दो घटक दलों में किसी स्थान को लेकर मतभेद होता है, तो किसी ऐसे तटस्थ व्यक्ति को बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति मध्यस्थता करे और जरूरत पड़ने पर अंतिम निर्णय करे। फेडरल पार्टी में द्रीएमके और असम गण परिषद को भी सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। फेडरल पार्टी का यह मतलब नहीं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। अगर इच्छा हो, तो जनता, लोकदल, जनमोर्चा और समाजवादी कांग्रेस को मिलाकर एक दल बन सकता है। नाम, झंडा और चुनाव चिह्न पर अड़ जाना विशुद्ध अपरिपक्वता है। कोई सम्माननीय रास्ता निकालना चाहिए। अजीत सिंह से मैं कहूंगा कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। वह संयम से काम लें। देवीलाल-मुलायम सिंह तथा जनमोर्चा दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से एकता स्थापित करें। इसमें पूरे विपक्ष का कल्याण है और उनका निजी हित भी।

नम्बूद्रिरीपाद दिन-रात भाजपा के सवाल पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। उनका तमिलनाडु में द्रमुक के साथ समझौता है। द्रमुक का मुस्लिम लीग के साथ। इधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में माकपा का लोकदल से गठबंधन था और लोकदल का भाजपा से। परोक्ष समझौते पर उन्हें आपत्ति नहीं है! महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और हिंदी भाषी प्रदेशों में माकपा-भाकपा की शक्ति नगण्य है। इसलिए उनके प्रलापों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीटी रणदिवे और नम्बूदिरीपाद का दिमाग १९२८ और ३६ के बीच में बन गया। उसके बाद उनमें जरा परिवर्तन नहीं आया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी में कई नेतृत्व परिवर्तन हुए और यहां कांग्रेस में भी। लेकिन माकपा नेता अभी तक स्टालिन के जमाने में ही वास करते हैं।

विपक्ष के पार्लियामेंटरी बोर्ड को चाहिए कि वह एक संक्षिप्त नीति वक्तव्य बनाये। तफसील में जाना बेकार है। सिद्धांतों को विधेयकों, प्रशासनिक कदमों और कार्यों में बदलना बहुत मुश्किल होता है। जनता पार्टी औद्योगिक विकेंद्रीकरण के बारे में प्रतिबद्ध थी। पर ढाई साल में कोई नया औद्योगिक नियंत्रण विधेयक वह पास नहीं करवा सकी। चुनाव सुधारों के बारे में यही हुआ। इसलिए कार्यक्रमिक बारीकी में उलझने से कोई लाभ नहीं। असली बात है, जनता पर जो नित्य अन्याय और जुल्म ढाया जा रहा है, उसको लेकर व्यापक जन आंदोलन संगठित करना। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक वर्ष आंदोलन और संघर्ष की चर्चा में ही बिता दिया। अब समय आया है, प्रत्यक्ष कर्म का। व्यापक जन आंदोलन के बिना समाज का अराजनीतिक हिस्सा आंदोलित नहीं होगा। विपक्ष का परंपरागत वोट ३० प्रतिशत है। ४२ प्रतिशत के बिना लोकसभा में बहुमत नहीं मिलेगा। यह १२ प्रतिशत कहां से आयेगा? जनमानस जब आंदोलित होगा, जैसे कि १९७४-७७ के बीच हुआ था, तभी यह अतिरिक्त १२-१३ प्रतिशत वोट विपक्ष को प्राप्त होगा और दिशाहीन, भ्रष्ट और खर्चीले राजीव प्रशासन से जनता को मुक्ति मिलेगी। ■

मास्को-शिखर वार्ता और राजीव की विदेश यात्रा

—भवानी सेनगुप्त

प्रधानमंत्री राजीव गांधी महासचिव मिखाइल गोर्बाचिव व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच संपन्न मास्को शिखर वार्ता के तुरंत बाद चार देशों की विदेश यात्रा पर गये। श्री गांधी ने सीरिया, पश्चिम जर्मनी, न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और हंगरी की यात्राएं कीं। उनकी उद्‌घोषणाओं और तीन देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के निशस्त्रीकरण और विकास अधिवेशन के समय एकत्र राजनयिकों से हुए विचार-विमर्श की गहरी जांच-परख दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने न केवल मास्को शिखर वार्ता की वास्तविक उपलब्धियों और भावी संभावनाओं का सुसंगत समर्थन किया, बल्कि महाशक्तियों के मध्य बढ़ते सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया जो भारत की विदेश नीति का मूलाधार है।

इस संबंध में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा सुनिश्चित पदचिह्नों का पालन किया। छठे दशक के आरंभ में नेहरू ने वाशिंगटन और मास्को के बीच तनाव शैथिल्य के लिए उठाये गये कदमों का स्वागत किया था। क्यूबाई प्रक्षेपास्त्र संकट के शांतिपूर्ण समझौते के परिणामस्वरूप भारत को अक्तूबर १९६२ में उत्तर-पूर्वी सीमा पर हुए चीनी सैनिक हमले के दौरान सोवियत संघ का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। १९६४ में नेहरू की मृत्यु के समय दोनों महाशक्तियों के बीच परस्पर मुठभेड़ के स्थान पर परस्पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए गंभीरतापूर्वक बातचीत शुरू हो गयी थी।

इस प्रयास को १९७२ में तब सफलता मिली, जब राष्ट्रपति निक्सन और लियोनिद ब्रेझनेव ने उस मास्को-विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये, जिसमें वाशिंगटन व मास्को के बीच नये संबंध विकसित करने की व्याख्या की गयी थी। तंनाव शैथिल्य के सूत्रपात का भारत ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारत सदैव दोनों महाशक्तियों से संबंध बनाने को उत्सुक था किंतु सोवियत संघ से उसकी मैत्री अमरीका को बेहद नापंसद थी। १९७० के तनाव-शैथिल्य ने निक्सन प्रशासन को भारत और सोवियत संघ के बीच अगस्त, १९७१ में हुई शांति-मैत्री संधि के बारे में न्यूनाधिक रूप में सदाशयपूर्ण दृष्टि प्रदान की। दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध की भारत से अधिक किसी देश ने आलोचना नहीं की है। शीतयुद्ध की शुरुआत अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि अमरीका की वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और ईरान में हार से हुई। किंतु अफगानिस्तान शीतयुद्ध का केन्द्र-बिंदु बन गया। अफगानिस्तान में महाशक्तियों की मुठभेड़ ने दूसरे शीतयुद्ध को सीधे दक्षिण एशिया में ला खड़ा किया। पाकिस्तान, सोवियत शक्ति और प्रभाव को रोकने के लिए अंतिम पंक्ति का देश बन गया। उसका अमरीका ने बहुत अधिक सैनिकीकरण किया और इससे भारत व पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ बढ़ गयी। राजीव गांधी सोवियत अमरीकी शिखर वार्ता का गर्मजोशी से समर्थन कर रहे हैं, जोकि रीगन प्रशासनं के दूसरे कार्यकाल में शुरू हुई। पहली शिखर वार्ता आज से ३० माह पूर्व जेनेवा में हुई, दूसरी रिक्जेविक में और तीसरी वाशिंगटन में। राजीव गांधी ने न सिर्फ इन शिखर वार्ताओं का स्वागत किया, बल्कि छोटें व मध्य दूरी के मारक परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के समझौते पर भारत का विशेष आभार भी प्रकट किया। सामरिक अथवा अंतरराष्ट्रीय दूरी तक मार करनेवाले परमाणु अस्त्रों का ५० प्रतिशत भाग समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर कई वर्ष पूर्व जेनेवा में वार्ता शुरू हुई थी। वाशिंगटन शिखर वार्ता में बातचीत काफी आगे बढ़ी। ऐसी आशा थी कि मास्को शिखर वार्ता के दौरान एक समझौता किया जायेगा, जिसके तहत मंहाशक्तियां अपने आधे सामरिक हथियार समाप्त कर देंगी। किंतु आधे सामरिक हथियार समाप्त करने के बाद भी जो परमाणु हथियार उनके पास शेष रहेंगे, वे संपूर्ण मानव जाति को कई बार समाप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। बहरहाल, मास्को में यह आशा पूर्ण न हुई। रीगन-समर्थक अमरीकी दक्षिण पंथ के विरोध के कारण समझौता न हो सका। पर दोनों महाशक्तियों के नेता मध्य दूरी तक मार करनेवाले परमाणु हथियारों को सीमित करनेवाले वाशिंगटन समझौते की पुनः पुष्टि करने में सफल हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि सामरिक शस्त्रों को समाप्त करनेवाली 'स्टार्ट संधि' (सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि) पर भी बातचीत जारी रखी जाये। आशा है कि अगस्त से पहले जब अमरीका में अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी-तब पांचवीं रीगन-गोर्बाचिव शिखर वार्ता भी आयोजित होगी। शिखर वार्ताओं का यह दौर चलता रहेगा, चाहे अगले अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश हों या माइकेल डुकासिस। राजीव गांधी की बीस वर्षों में संपूर्ण निशस्त्रीकरण की तीन चरणों की योजना, जिसकी घोषणा उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष अधिवेशन में की। कुल मिलाकर मिखाइल गोर्बाचिव के निशस्त्रीकरण प्रस्तावों से भिन्न नहीं है। पर राजीव गांधी की तीन चरणों की योजना में एक विशेषता है जो गोर्बाचिव की साहसिक और कल्पनाशील पहलकदमी में नहीं है। भारतीय योजना में विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण के तहत सभी परमाणु व गैरपरमाणु शक्तियों को विशिष्ट चरणों में संगलन करने और परमाणुरहित विश्व का निर्माण करने का प्रावधान है। श्री गांधी ने एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा यह मांग भी पेश की है कि १९९० में

वर्तमान अस्त्र अप्रसार संधि (एनएनपीटी) पर पुनः विचार किया जाये। २० साल पहले भारत समेत अनेक राष्ट्रों द्वारा विरोध के बावजूद हस्ताक्षरित वर्तमान एनएनपीटी ने अपना महत्व खो दिया है। परमाणु शक्तियों ने परमाणु हथियारों में कमी करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं निभायी है। न ही उन्होंने कोई ऐसे कदम उठाये हैं, जिनसे इस संधि के भेदभावपूर्ण प्रावधान, जोकि गैरपरमाणु देशों को दी जानेवाली तकनीकी जानकारी और कच्चे माल की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, में सुधार हो सके। यदि श्री गांधी के प्रस्ताव पर अमल होता है, तो एक नयी एनएनपीटी संधि द्वारा समस्त परमाणु शक्तियों का यह दायित्व हो जायेगा कि वह अपने परमाणु भंडारों का विनाश करें। गैरपरमाणु शक्तियों को भी यह गारंटी देनी होगी कि वे परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगी। यह भारतीय प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन व फ्रांस में तो शायद काल्पनिक उड़ान माना जायेगा, किंतु यदि भारतीय राजनय इस विषय में अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो १९९० की एनएनपीटी समीक्षा कांफ्रेंस में भाग लेनेवाले अनेक राष्ट्र भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

मास्को शिखर वार्ता : भारत और तीसरी दुनिया के अन्य देशों के लिए अमरीका और सोवियत संघ के बीच क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने अथवा उसका समाधान ढूंढ़ने के विषय पर जारी गंभीर वार्ता का विशेष महत्व है। मास्को शिखर वार्ता में यह बातचीत पहले से कहीं अधिक गहरी और सार्थक रही है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अफगान मसले पर १४ मार्च को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो 'जेनेवा करार' हुआ और जिसकी गारंटी सोवियत संघ और अमरीका ने ली थी, उसने इस वार्ता में अहम भूमिका निभायी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों, जो कि गत ४० वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ विकासशील देशों में २०० से अधिक युद्धों और मुठभेड़ों में संलग्न रही हैं, ने पहली बार एक ऐसी संधि को कारगर बनाने के लिए संयुक्त हस्ताक्षर किये हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मुठभेड़ों को समाप्त करना है।

जहां तक क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के लिए हर संभव उपाय करने का सवाल है, अफगानिस्तान का मसला अकेला नहीं है। क्षेत्रीय संघर्षों को यथा-संभव सुलझाने का प्रयास यकायक विश्वव्यापी हो गया है। गत चार-पांच महीनों में बहुस्तरीय बातचीत द्वारा अंगोला और मोजांबिक के बीच छिड़े युद्ध, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का भी सैनिक हस्तक्षेप है, को समाप्त करने के प्रयास भी हो रहे हैं। इसके तहत ३५ हजार उन क्यूबाई सैनिकों को भी वापस बुलाने की बातचीत चल रही थी जो इन दोनों मार्क्सवादी सरकारों की मदद प्रतिक्रांतिकारियों और दक्षिण अफ्रीकी सैन्य बल से निपटने में कर रहे थे। वियतनाम ने भी कंपूचिया से अपने आधे सैनिक अर्थात ५० हजार सैनिक वापस बुलाने की साहसिक घोषणा की है। शेष आधी वियतनामी सेना वहां रह जायेगी। वह कंपूचियाई देखरेख के तहत रहेगी तथा १९९० के पूर्व वापस बुला ली जायेगी। मास्को शिखरवार्ता के दौरान अमरीका ने वियतनाम के इस निर्णय का स्वागत किया है। इसी प्रकार मध्य अमरीका में निकारागुआई और कांट्रास सैनिकों के मध्य जो युद्धविराम हुआ है, वह बरकरार है। इसी प्रकार आर्यास की शांति योजना, जिसमें मध्य अमरीकी समस्याओं के समाधान का प्रावधान बिना अमरीकी दखलंदाजी के है, को लैटिन अमरीका व स्वयं अमरीका का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गत ४० वर्षों से जारी अरब-इस्राइल संघर्ष के समाधान के विषय में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के मुद्दे पर बातचीत भी लगभग सहमति के निकट पहुंच गयी है। आज इस मसले पर सोवियत संघ व अमरीका के विचारों में काफी साम्य है। दोनों महाशक्तियां आज इस बात पर रजामंद हैं कि इस्राइल १९६७ के दौरान अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली करे। साथ ही दोनों देश यह भी मानते हैं कि अरब राष्ट्र इस्राइल के 'समान सुरक्षा के अधिकार' को मान्यता प्रदान करें। यदि इस वर्ष या अगले वर्ष अमरीका और सोवियत संघ की संयुक्त अध्यक्षता में यह मध्यपूर्व सम्मेलन आयोजित होता है, तो शायद यह हमारे समय के सबसे लंबे और जटिल क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

अफगान करार : दोनों महाशक्तियों के मध्य क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने की बातचीत जारी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगान करार पर सही और पूरे तौर पर अमल हो। हाल की तीन देशों व संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी यात्रा के दौरान श्री गांधी ने अफगान करार पर अमल करने के महत्व पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह मुजाहिदों (अफगान शरणार्थियों) को अमरीकी हथियार प्रदान कर, उन्हें स्वदेश लौटते सोवियत सैनिकों की हत्या करने के लिए उकसा रहा है और करार का उल्लंघन कर रहा है। श्री गांधी ने अमरीका से मांग की कि वह पाकिस्तान को कुछ सप्ताह पूर्व हस्ताक्षरित जेनेवा समझौते को नष्ट करने से रोके।

करार में तोड़फोड़ करने की पाकिस्तानी कोशिश की भर्त्सना सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने भी की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्वदेश लौटते सोवियत सैनिकों पर मुजाहिदों के हमले जारी रहे, तो मास्को को अपनी सेनाओं के वापसी कार्यक्रम में रद्दोबदल करना पड़ेगा। राजीव गांधी द्वारा इसी प्रकार की चेतावनी से ऐसी धारणा बन सकती है कि भारत और सोवियत संघ अफगानिस्तान के मामले में एक साथ काम कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के तहत ऐसा कर रहा है। 'न्यूयार्क टाइम्स' से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काबुल में कट्टरपंथी शासन की स्थापना न केवल भारत के हितों के विरुद्ध होगी, बल्कि अमरीका और सोवियत संघ के भी हितों के विरुद्ध होगी, क्योंकि वह तेहरान के कट्टरपंथी शासन के साथ एकजुट होकर एक ऐसी क्रांतिकारी अस्थिरता पैदा कर सकता है जो अरब प्रायद्वीप के तथाकथित उत्तरी श्रेणी के बाहर तक फैल जाये। यही आशा की जाती है कि समय रहते अमरीका इस खतरे से आगाह हो जायेगा। अमरीका आज भी पाकिस्तान के जनरल जिया-उल-हक को जेनेवा संधि को तहसनहस करने से रोकने की शक्ति रखता है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि एक बार मुजाहिदों के पास अमरीकी हथियारों का भंडार एकत्र हो जाये और काराकोरम में उनकी व्यापक घुसपैठ हो जाये, तो वह जनरल जिया और अमरीका के नियंत्रण से मुक्त हो जायेंगे। यदि ऐसा दिन आया, तो पाकिस्तान के लिए सिर पकड़कर बैठने और अमरीका के लिए पछताने के अलावा कोई चारा शेष नहीं रह जायेगा। ■

ये रहे दो खास कारण जिनकी वजह से मनाली वेंगसरकर ने विजिल साबुन अपनाया.

अपने परिवार की तंदुरुस्ती की हिफ़ाजत कीजिए. गोदरेज का नया साबुन विजिल ले आइए.

"दिलीप और अपने लाडले नकुल के आसपास ही तो मेरी दुनिया है", कहती हैं मनाली वेंगसरकर. "और चूंकि मेरी तरह आपके लिए भी अपने परिवार की तंदुरुस्ती ही सब कुछ है, आप हर चीज़ सोच-समझकर ही अपनाना चाहेंगी, चाहे नहाने का साबुन ही क्यों न हो.

इसीलिए तो मैंने विजिल साबुन ही चुना. विजिल में कुदरती तेल हैं जो त्वचा और तंदुरुस्ती की रक्षा करनेवाली अपनी खूबियों के लिए सदियों से मशहूर हैं. यह नरम मखमली झाग देता है. और इसकी खुशबू के तो बस क्या कहने! बेशक, मेरे परिवार की तंदुरुस्ती के लिए विजिल ही एकमात्र भरोसे का साबुन है."

Godrej
VIGIL
THE FAMILY HEALTH SOAP

विजिल-गोदरेज का नया साबुन परिवार की तंदुरुस्ती का रखवाला.

गोदरेज

'उस्ताद मुख्यमंत्री' क्यों हटे ?

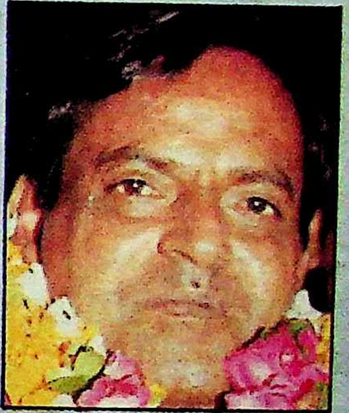

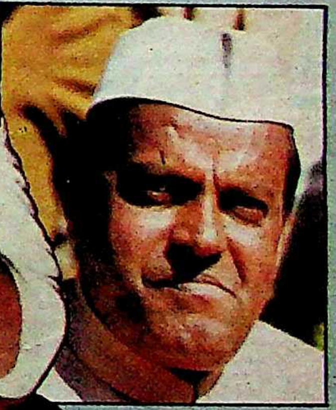

छाया: मनमोहन शर्मा

गोरखपुर के अत्यंत पिछड़े गांव हरनही में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे वीर बहादुर सिंह उस प्रांत के मुख्यमंत्री बने जो देश की राजनीति की धारा मोड़ने की शक्ति रखता है। ५३ वर्षीय वीर बहादुर सिंह विशाल और राजनीतिक उथल-पुथल से भरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि वह उतने समय तक अपनी कुरसी पर जमे रहे, जितने समय तक पिछले १२ वर्षों में कोई मुख्यमंत्री नहीं टिका है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री के रूप में शामिल करना भी आवश्यक समझा गया, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने हरनही से दिल्ली तक की राजनीतिक यात्रा मात्र मेहनत और नेता के प्रति निष्ठा के पाथेय के सहारे ही नहीं तय की है, उन्होंने जोड़-तोड़, तिकड़म, मौकापरस्ती और चापलूसी जैसी उन वैसाखियों का भी सहारा लिया है जो आज की सिद्धांतहीन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं, लेकिन इन अनिवार्यताओं को पूरा करनेवाले तो उत्तर प्रदेश में और भी नेता थे, फिर वीर बहादुर ने ही ऐसी क्या उस्तादी दिखायी कि वह मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंच गये? १००५ दिनों तक हर संकट से उबरते आ रहे इस उस्ताद मुख्यमंत्री को हटना क्यों पड़ा? मामूली से गैरमामूली बने देश के बहु-चर्चित राजनेता के सादा जीवन, टेढ़ी राजनीति और निराली कार्यशैली का अजय कुमार द्वारा अंतरंग जायज़ा :

छाया: मनमोहन शर्मा

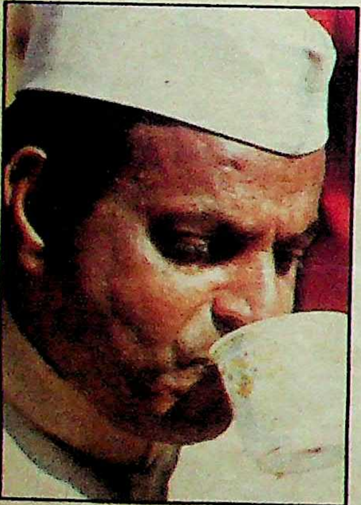

१८ जून को जब उत्तर प्रदेश के तीनों उपचुनावों के परिणाम सामने आ गये, तो विपक्षी दल के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली। इस पर वीर बहादुर का जवाब था, "उप चुनावों में हार-जीत का कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ता है। रामनरेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कई उपचुनाव हुए थे। उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ? जब गढ़वाल के उपचुनाव में बहुगुणाजी जीत गये थे, तो क्या वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था ? उपचुनावों में पार्टी की हार से मुख्यमंत्री कभी इस्तीफा नहीं देता है।"

ठीक इसी तरह की बात २३ जून की शाम इंका मुख्यालय, २४-अकबर रोड में पत्रकारों से घिरे गुलाम नबी आजाद ने कही। उन्होंने कहा, "उपचुनाव हम क्यों और कैसे हारे, इसकी समीक्षा की जा रही है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनाव में हार के कारण वीरबहादुर, मुख्यमंत्री-पद से नहीं हटेंगे। उनके द्वारा इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चाहें, तो मुझे कोट करते हुए यह समाचार छाप सकते हैं।"

यह भी एक विचित्र संयोग ही था कि जिस समय गुलाम नबी आजाद पत्रकारों से दावे के साथ वीर बहादुर के न हटने की बात बता रहे थे, ठीक उसी समय वीर बहादुर, राजीव गांधी के सामने बैठे चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहे थे।

निर्णायक मुलाकात : २१ जून की दोपहर वीर बहादुर लखनऊ से मेरठ गये थे। वहां एक दिन पूर्व बस दुर्घटना में दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। २० जून की शाम श्रीनगर (गढ़वाल) में भी एक बस दुर्घटना में २६ लोगों की जान चली गयी थी। दोनों स्थानों का मौका मुआइना करने के बाद रात्रि में वीर बहादुर दिल्ली पहुंच गये। यूपी निवास से पीएम हाउस फोन कर उन्होंने 'दिल्ली दरबार' से मिलने का समय मांगा। २२ जून को काफी प्रयास के बाद भी वीर बहादुर की राजीव गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी, जबकिं लोकपति त्रिपाठी से पीएम की मुलाकात उसी दिन हो चुकी थी। २३ जून को गोपीनाथ दीक्षित, नरेन्द्र सिंह, सुनील शास्त्री, हरिकिशन शास्त्री और लोकपति त्रिपाठी सहित उत्तर प्रदेश के कई नेताओं की राजीव गांधी से मुलाकात हुई। सबने अपने-अपने ढंग से उपचुनाव में हार के कारण बताये। काफी प्रयास के बाद शाम ठीक पांच बजकर सात मिनट पर वीर बहादुर की राजीव गांधी से मुलाकात हुई। ४२ मिनट तक एकांत में बातें होती रहीं। बीच में माखनलाल फोतेदार और बूटा सिंह ने भी कुछ देर के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। उसके बाद जब वीर बहादुर, पीएम हाउस से निकले, तो उनके चेहरे पर एक उदासी थी। वह सीधे यूपी निवास पहुंचे। वहां अनेक लोग मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनमने भाव से वीर बहादुर प्रतीक्षारत लोगों की उपेक्षा कर पहली मंजिल के अपने कक्ष में चले गये। कमरा उन्होंने अन्दर से बंद कर लिया। प्रतीक्षारत लोगों को निजी सहायक ने बता दिया, "मुख्यमंत्रीजी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, कल सुबह लखनऊ में मिलेंगे।"

रात्रि करीब पौने १० बजे वीर बहादुर दिल्ली से लखनऊ आ गये। कुछ ही देर बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुला ली जो देर रात तक चलती रही। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण फाइलें निपटायीं। अधिकारियों की बैठक से पूर्व जब कुछ पत्रकारों ने वीर बहादुर से मिलकर यह पूछा, "दिल्ली में क्या हो रहा है," तो वह बनावटी मुस्कान

> काफी प्रयास के बाद शाम ठीक पांच बजकर सात मिनट पर वीर बहादुर की राजीव गांधी से मुलाकात हुई। ४२ मिनट तक एकांत में बातें होती रहीं। बीच में माखनलाल फोतेदार और बूटा सिंह ने भी कुछ देर के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। उसके बाद जब वीर बहादुर, पीएम हाउस से निकले, तो उनके चेहरे पर एक उदासी थी।

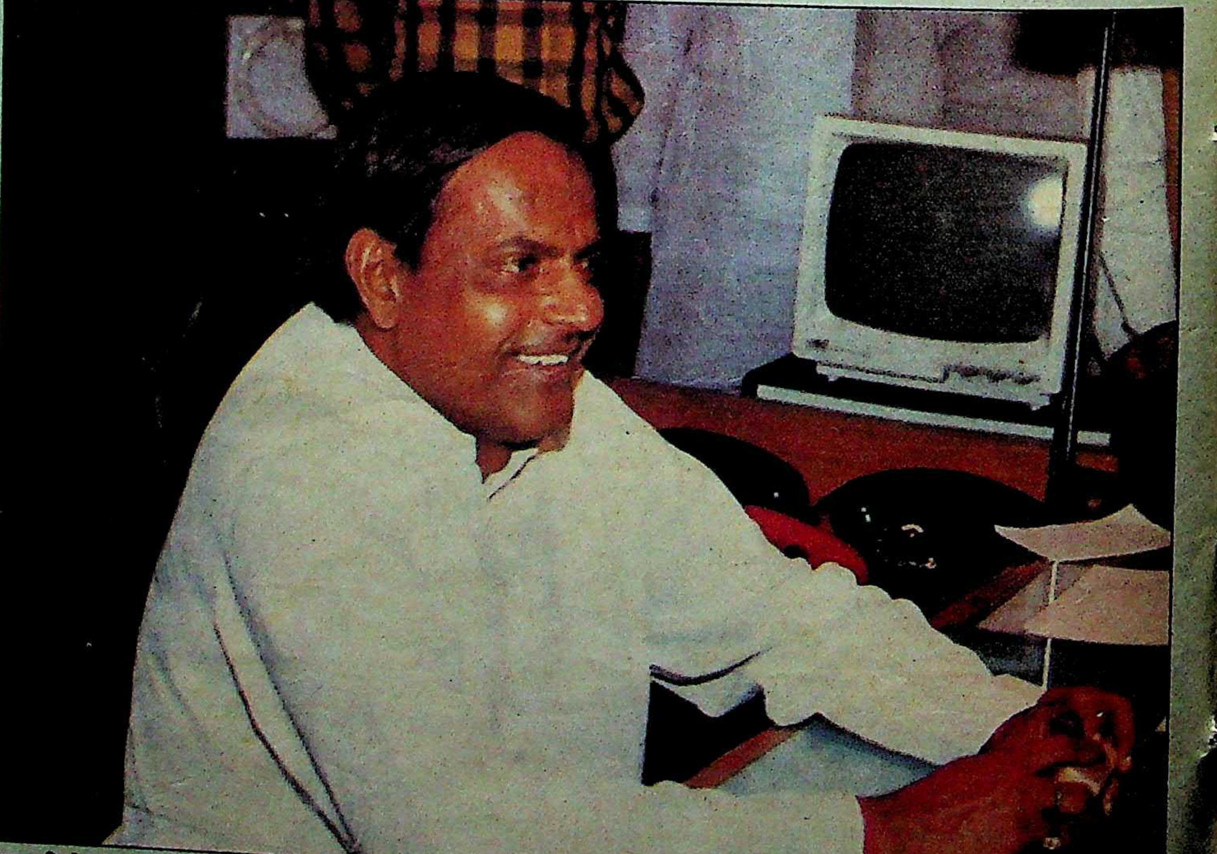

आसानी से कुरसी नहीं छोड़ी : वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री-कार्यालय में

छाया: राजेंद्र कुमार

लाते हुए, बोले, "मुझे क्या मालूम ?" इस सवाल पर कि क्या आप इस्तीफा देकर दिल्ली जा रहे हैं, वीर बहादुर का जवाब था, "अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है।"

लेकिन जिस तरह वीर बहादुर ने दिल्ली से लौटते ही रहस्यमय ढंग से अधिकारियों की बैठक की थी, उससे यह साफ लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने उनसे मुख्यमंत्री-पद छोड़ने को कह दिया है।

ऐसे दिया इस्तीफा : २४ जून की सुबह कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर काफी गहमा-गहमी थी, क्योंकि कई अखबारों में यह खबर छप गयी थी कि "वीर बहादुर को इस्तीफा देने का निर्देश मिला।" तमाम पत्रकार भी वहां आ जुटे थे। लेकिन वीर बहादुर, अपने शयनकक्ष से बाहर नहीं निकले। करीब सवा दस बजे दिल्ली से गुलाम नबी आजाद का फोन आया। आजाद ने फोन पर वीर बहादुर से क्या कहा यह तो पता नहीं, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठे लोगों को शयनकक्ष से वीर बहादुर की यह आवाज जरूर सुनायी पड़ी, "मैंने तो रात में ही लिख लिया था, आपने कहा था कि फोन पर बात होने के बाद देने जाऊं। अब आपका फोन आ गया है, मैं जा रहा हूं।"

कोई दस मिनट बाद ही वीर बहादुर शयन कक्ष से तेजी से निकले और पोर्टिको में खड़ी कार की ओर बढ़ गये। ड्राइंग रूम में बैठे कई विधायक और पत्रकार लपक कर कार तक पहुंचे, लेकिन बिना किसी की ओर देखे वह कार में बैठ गये। राज्यमंत्री रामनरेश शुक्ला और सांसद राणावीर सिंह ने भी कार का दरवाजा खोलकर मुख्यमंत्री से कुछ बात करनी चाही, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, "फिर बात करूंगा, अभी जल्दी में हूं।"

वीर बहादुर के हाथ में एक लिफाफा था, जिस पर उनकी अपनी हस्तलिपि में 'महामहिम राज्यपाल' लिखा हुआ था। लिफाफा देखते ही लोगों ने खत का मजमून भांप लिया। वीर बहादुर की कार के पीछे-पीछे कई गाड़ियां लग गयीं।

यह भी एक विडम्बना ही थी कि जब वीर बहादुर अपना इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे, तो उसे स्वीकार करने के लिए राज्यपाल उपस्थित ही नहीं थे। राजभवन में वीर बहादुर की अगवानी करने वाला भी कोई नहीं था। उनके पहुंचने पर आगंतुक कक्ष खुलवाया गया, जहां साथ गये कुछ पत्रकारों के साथ बैठकर वह गपशप करने लगे। मुख्यमंत्री की सचिव नीरा यादव और सूचना निदेशक अशोक प्रियदर्शी भी साथ आये थे। राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ उस समय नैनीताल में थे। वीर बहादुर ने कहा, "राज्यपाल से नैनीताल फोन मिलवाकर बात कराओ।"

टेलीफोन की 'हाट लाइन' खराब थी। राजभवन में कोई अधिकारी भी नहीं था। काफी प्रयास के बाद भी जब टेलीफोन नहीं मिला, तो वीर बहादुर ने पूछा, "यह कैसा राजभवन है, यहां कोई अधिकारी ही नहीं रहता। टेलीफोन भी काम नहीं करता।"

थोड़ी देर में राज्यपाल के संयुक्त सचिव पीएल लोई आ गये। ठीक पौने ग्यारह बजे वीर बहादुर ने मुख्यमंत्री-पद से त्यागपत्र वाला लिफाफा लोई को थमा दिया। इसी के बाद वह अपनी सचिव नीरा यादव से बोले, "आप लोई को साथ लेकर स्टेट प्लेन से नैनीताल चली जायें। वहां यह इस्तीफा राज्यपाल को सौंप कर उन्हें अपने साथ लेती आयें। राज्यपाल को बता देना कि कल सुबह नये मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी है।"

वीर बहादुर राजभवन से जब लौटे, तो तनाव मुक्त थे। लौटते समय मैंने उनसे कार में पूछा—यह सब अचानक

छाया : सुनील सक्सेना

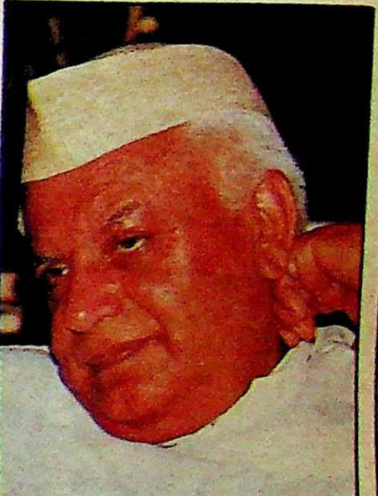

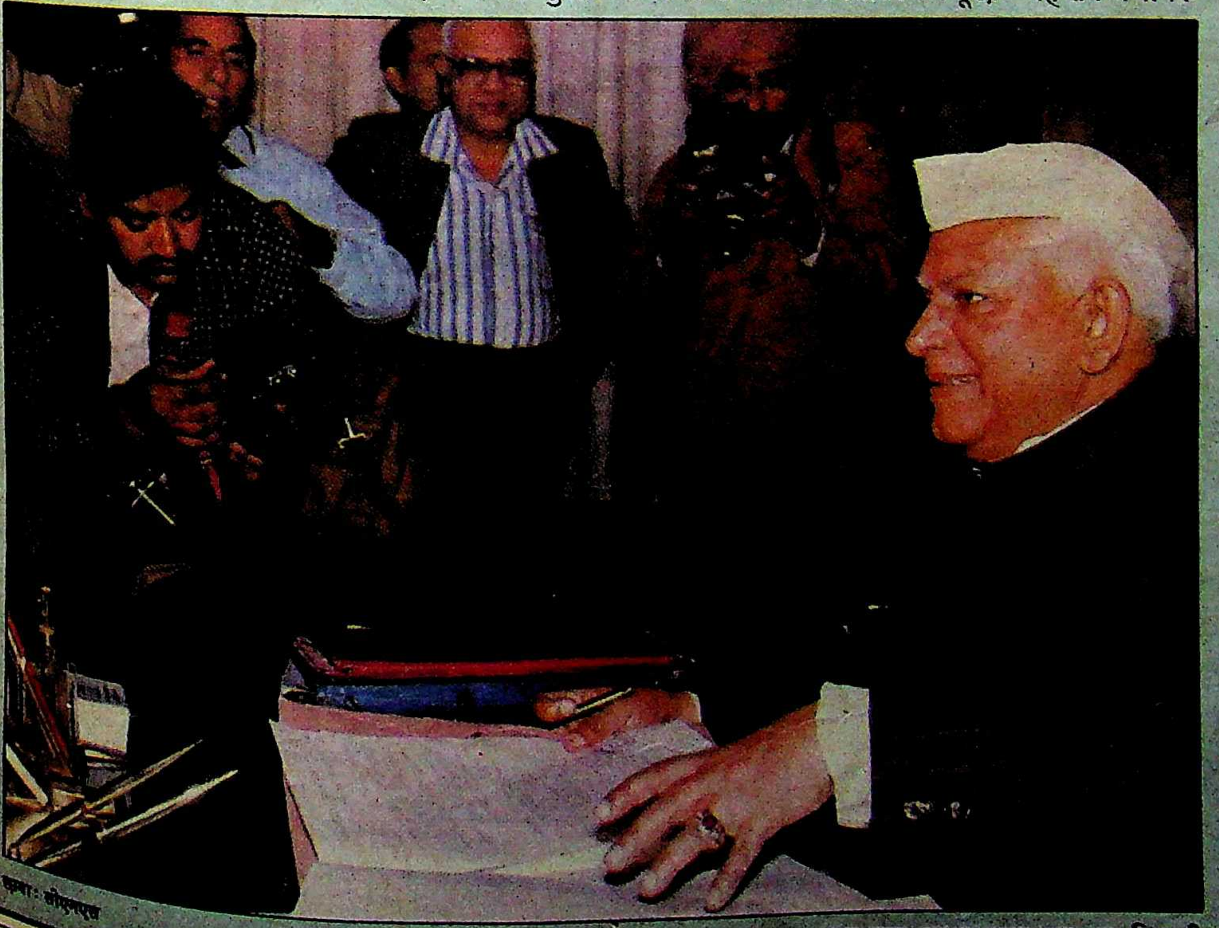

छाया : [illegible]

एक मात्र तुरुप : नारायण दत्त तिवारी

> वीर बहादुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से मंत्री बनाने की अनुमति उन्हें नहीं थी। यही नहीं, काशीपुर में उपचुनाव हारने के बाद अम्मार रिजवी को वीर बहादुर मंत्री-पद से हटाना चाहते थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी और माखनलाल फोतेदार के दबाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सके थे।

कैसे हो गया? वीर बहादुर झुंझलाते हुए बोले, "सब नाटक हो रहा है। तिवारीजी और उनकी मंडली मुझे हटाना चाहती थी। वे लोग सफल हो गये। कल पीएम ने कहा इस्तीफा दे दो, मैंने दे दिया। जैसे आया था, वैसे जा रहा हूं।"

वीर बहादुर को इस बात का मलाल था कि उन्हें इलाहाबाद के चुनाव को मुद्दा बना कर हटाया गया है। उनका कहना था, "इस चुनाव में जितनी मेहनत मैंने की, उसकी बीस प्रतिशत भी दूसरे लोग करते, तो इतना खराब परिणाम न होता। जिन लोगों ने चुनाव में कोई काम नहीं किया, उलटे पार्टी उम्मीदवार को बेसिरपैर के बयान देकर हरवाया है, वही अब यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव मैंने हरवा दिया।"

प्रधानमंत्री द्वारा तारीफ: विचित्र बात यह है कि वीर बहादुर के इस्तीफा देने से ठीक चार महीने पूर्व २० फरवरी, १९८८ को लखनऊ में आयोजित इंका की विशाल रैली में राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था, "मैं अपने मंत्रीजी (मुख्यमंत्री) का काफी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी भीड़ (रैली) इकट्ठी की है। कांग्रेस के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि उसके पास वीर बहादुर जैसे जमीन के आदमी हैं।" प्रधानमंत्री ने इसी तरह का प्रमाण पत्र वीर बहादुर को पहली मई को आयोजित कानपुर रैली में दिया था। आखिर, सार्वजनिक प्रमाण पत्र के दो महीने के अन्दर वीर बहादुर जमीन के बजाय आसमान के आदमी कैसे हो गये?

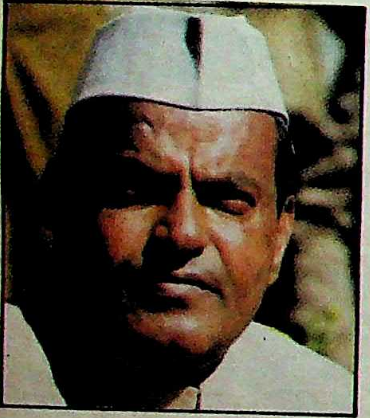

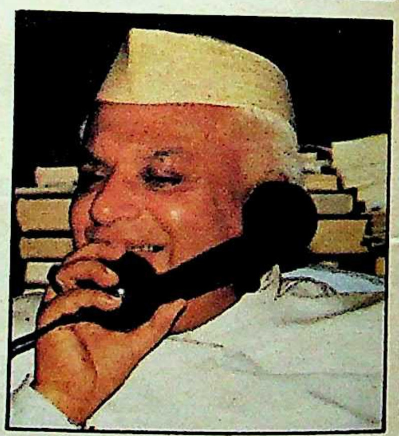

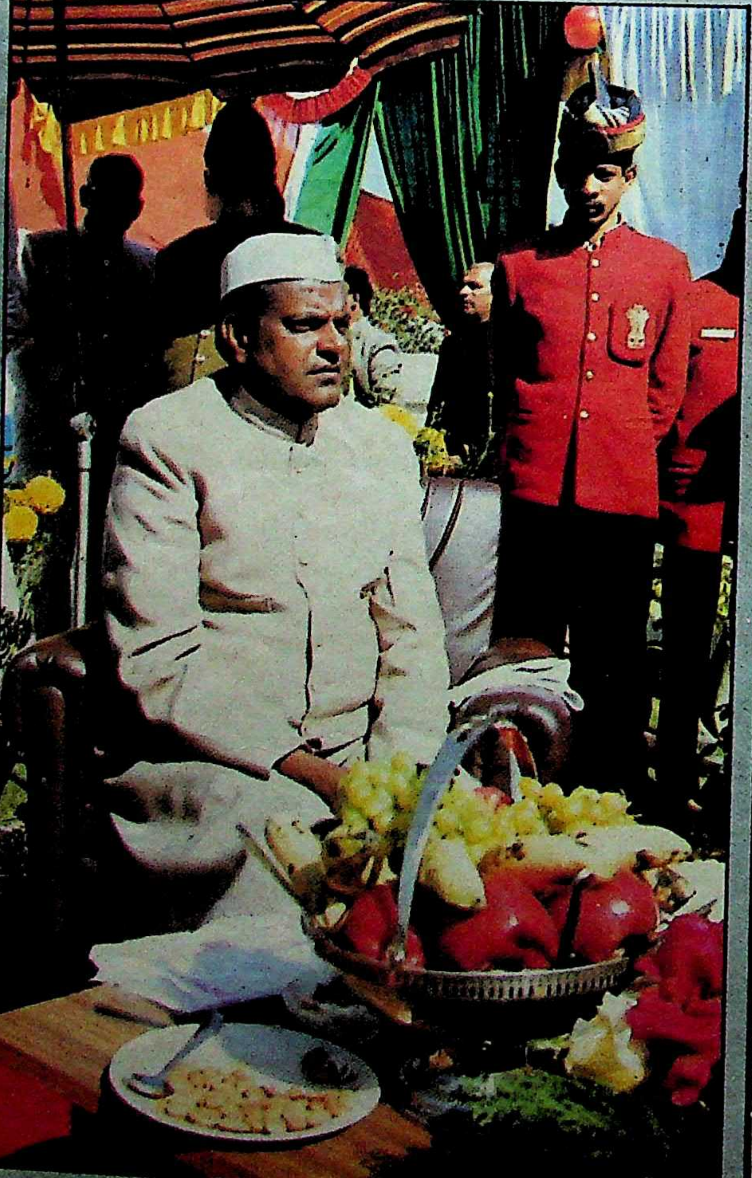

आम आदमी से खास आदमी तक की यात्रा: एक समारोह में वीर बहादुर सिंह

> अपनी तिकड़म और कूटनीति से हर आड़े मौके पर अपने को बचाकर निकल जानेवाले वीर बहादुर सिंह मुसीबत में फंसते चले गये। उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया उत्तर प्रदेश में इंका के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने।

> तिवारी और फोतेदार ने मोहसिना किदवई और ब्रह्मदत्त की सहायता से पिछले कुछ समय से दिल्ली में अपनी जो सशक्त लाबी बना ली थी, वीर बहादुर उस लाबी की ताकत का सही अंदाज नहीं लगा सके थे। इस लाबी को मदद गोपी अरोड़ा कर रहे थे।

दरअसल, वीर बहादुर को हटाने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया। दो महीने पूर्व ही उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने का मन आलाकमान ने बना लिया था। जिसका स्पष्ट संकेत इलाहाबाद के उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन के समय मिल गया था। सुनील शास्त्री वीर बहादुर की पसंद के उम्मीदवार नहीं थे।

वीर बहादुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से मंत्री बनाने की अनुमति उन्हें नहीं थी। यही नहीं, काशीपुर में उपचुनाव हारने के बाद अम्मार रिजवी को वीर बहादुर मंत्री-पद से हटाना चाहते थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी और माखनलाल फोतेदार के दबाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सके थे। इसी तरह ११ मई, १९८८ को वीर बहादुर ने पत्रकारों के सामने यह घोषणा की थी," उपचुनाव के बाद ही मैं अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करूंगा।" लेकिन अगले ही दिन 'ऊपरी दबाव' से उन्हें श्रीमती सुशीला रोहतगी को मंत्री बनाना पड़ा था।

उत्तर प्रदेश के जो भी मंत्री या नेता केन्द्र में हैं, उनमें से एक भी वीर बहादुर का कभी हितैषी नहीं रहा। यही वजह थी कि अरुण नेहरू के प्रयास से (हालांकि वीर बहादुर ऐसा नहीं मानते) सितम्बर १९८५ में जब वीर बहादुर को मुख्यमंत्री की गद्दी मिली थी, तभी से यह चर्चा शुरू हो गयी थी कि वीर बहादुर अब गये तब गये। दिल्ली दरबार में अनेक लोगों द्वारा कान भरे जाने के बावजूद वीर बहादुर १००५ दिन मुख्यमंत्री बने रहे, जो एक रिकार्ड है। राज्य के पहले चार मुख्यमंत्रियों—गोविंद बल्लभ पंत, सम्पूर्णानंद, चंद्रभान गुप्त और सुचेता कृपलानी को छोड़कर कोई भी लगातार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहा (देखिए बाक्स)। राजीव गांधी का पूर्ण विश्वास प्राप्त होने के कारण ही वीर बहादुर इतने दिनों तक मुख्यमंत्री की कुरसी पर बने रहे और पूरे कार्यकाल में दिल्ली दरबार से मिलने वाले आदेशों को निष्ठापूर्वक शिरोधार्य करते रहे। यही वजह थी कि दिल्ली में उनके खिलाफ कान भरने वालों की संख्या बढ़ती गयी। दिल्ली दरबार में वह अपनी कोई अलग लाबी नहीं बना पाये थे। अंततोगत्वा राजीव गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में केन्द्र में बुला लेने का फैसला कर लिया।

राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि जिस तरह १९७५ में हेमवती नंदन बहुगुणा, उच्च न्यायालय में श्रीमती गांधी के विरुद्ध राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका का फैसला श्रीमती गांधी के पक्ष में कराने में असफल होने के कारण मुख्यमंत्री-पद से हटा दिये गये थे, ठीक उसी तरह वीर बहादुर भी उपचुनावों को सरकारी अधिकारियों की मदद से जिताने में असफल होने की वजह से ही पद से हटाये गये हैं। उस समय यशपाल कपूर और संजय गांधी ने इंदिराजी से कहा था, "अगर बहुगुणाजी दिल से चाहते, तो वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में करा सकते थे।" अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ठीक इसी तरह का काम गुलाम नबी आजाद, संतोष मोहन देव, सीताराम केसरी और शास्त्री बन्धुओं सहित तमाम लोगों ने यह कह कर किया, "अगर वीर बहादुर चाहते, तो चुनाव में प्रशासन, पार्टी की मदद जरूर करता।" लेकिन उस समय बहुगुणा को हटाकर कुछ नहीं बनाया गया था, जबकि वीर बहादुर को केन्द्र में संचार मंत्री का पद दे दिया गया है।

रिकार्ड तोड़ मुख्यमंत्री : यह भी तथ्य है कि जहां १९६७ के बाद उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाले मुख्यमंत्रियों में वीर बहादुर सिंह रहे हैं, वहीं उनके 'राज' में जो कुछ हुआ, वह इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ था। आजादी के बाद कभी किसी मुख्यमंत्री ने अयोध्या की रामजन्म भूमि का ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं की थी। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में उत्तर प्रदेश, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीन-तीन बार की कौन कहे, एक बार भी पूरे देश में आंकड़ों के मायाजाल के कारण प्रथम नहीं आ पाया था। दूसरे किसी मुख्यमंत्री के जमाने में पीएसी ने मलियाना और हाशिमपुरा जैसे कत्लेआम करने की हिम्मत नहीं की थी। सिर्फ एक रेल दुर्घटना के कारण लालबहादुर शास्त्री रेलमंत्री-पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गये थे, लेकिन पिछले पौने तीन सालों में कुंभ (हरिद्वार), राम की पैड़ी (अयोध्या), चित्रकूट और पूर्णागिरि में करीब दो सौ लोग सरकार की बदइंतजामी से मरे, फिर भी वीर बहादुर ने दुख प्रगट करते हुए इस्तीफा नहीं दिया था।

वीर बहादुर ने मेरठ का किसान आन्दोलन देखा और कर्मचारियों की तीन लम्बी हड़तालें वह झेल गये। बम्बई की सिनेमा हड़ताल ने महाराष्ट्र सरकार को तो हिलाकर रख दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ३१ दिनों तक चलने वाली सिनेमा हड़ताल को वीर बहादुर एक तमाशाई की तरह देखते रहे थे। इसके बावजूद राजीव गांधी उन्हें कुशल मुख्यमंत्री होने का प्रमाणपत्र देकर बड़े गर्व से कहते रहे कि पार्टी के पास वीर बहादुर जैसे जमीन के आदमी हैं। आखिरकार, वह कौन सा करिश्मा था, जिसकी वजह से वीर बहादुर अपनी प्रशासनिक असफलताओं को राजनीतिक सफलता साबित करने में अब तक कामयाब होते रहे थे।

अतीत : वीर बहादुर की इस सफलता को सही ढंग से आंकने के लिए उनके सम्पूर्ण जीवन का मूल्यांकन करना जरूरी है जो चापलूसी, अवसरवादिता, तिकड़म और उस्तादी का एक अद्भुत मिश्रण है। २१ वर्ष पूर्व पहली बार विधायक चुने जाने के बाद से वीर बहादुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो वीर बहादुर शुरू से ही ऊंची छलांग लगाने की घात में थे, लेकिन उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने का पहला अवसर १९७५ में इमरजेंसी के दौरान मिला। उन्हीं दिनों श्रीमती गांधी ने संजय गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला किया था। संजय के लिए रायबरेली से सटा तथा काफी पिछड़ा क्षेत्र अमेठी चुना गया था। श्रीमती गांधी ने नारायण दत्त तिवारी को निर्देश दिया था कि अमेठी क्षेत्र में संजय का सहयोग देने के लिए किसी मंत्री को लगाया जाये। तिवारीजी ने वीर बहादुर जैसे सीधे-सादे आदमी को इस काम में लगा दिया था।

धीरे-धीरे वीर बहादुर संजय गांधी के स्नेहपात्रों में एक हो गये थे। इसका मुख्य कारण यह था कि वह कभी भी संजय गांधी या उनकी मित्र मंडली से बहस या जिरह नहीं करते थे। जिस तरह

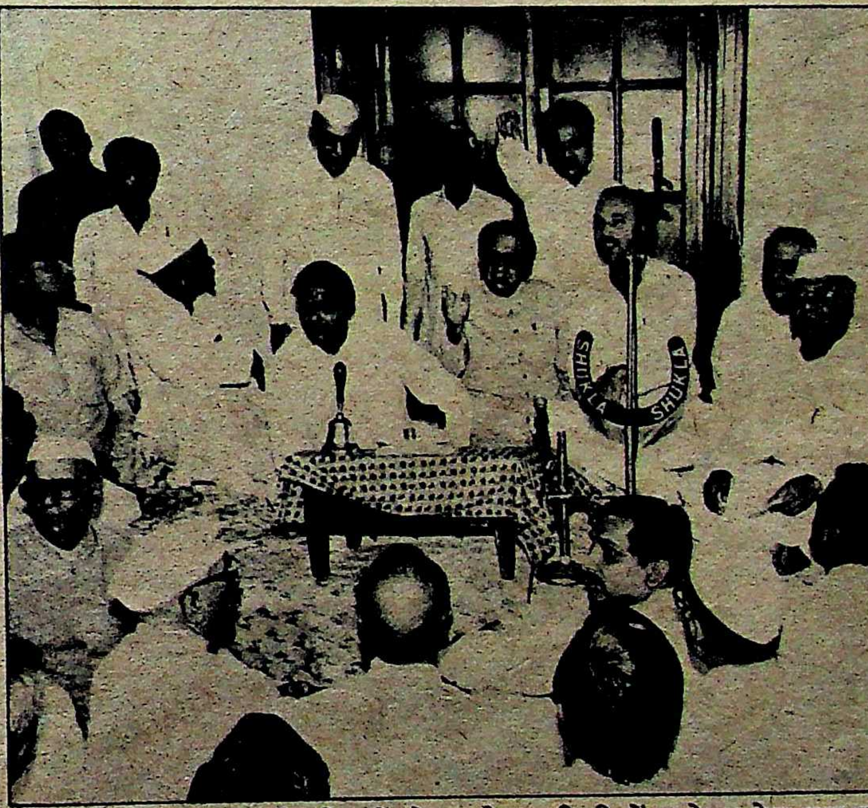

नेता चुनने की रस्म अदायगी : तिवारी को उनकी अनुपस्थिति में रातोरात नेता चुना गया

साक्षात्कार/वीर बहादुर सिंह

जैसे आया था, वैसे ही चला गया

एक हजार पांच दिन के अपने शासनकाल में वीर बहादुर सिंह तरह-तरह के राजनीतिक हुनर दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी देते आ रहे थे। लेकिन जिन वीपी सिंह की वजह से दिल्ली दरबार में वीर बहादुर का दबदबा बढ़ा था, अंततः वही उन्हें ले डूबे।

वीर बहादुर को यह अच्छी तरह पता था कि इलाहाबाद का उपचुनाव उनके गले की हड्डी बनेगा, इसीलिए उसे टलवाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। हर मौके पर ज्योतिषियों, पंडितों और तंत्र-मंत्र का सहारा लेकर चलने वाले वीर बहादुर को कोई भी ज्योतिषी यह बात पक्की तौर पर नहीं बता सका था कि इलाहाबाद उपचुनाव के एक सप्ताह के अंदर ही उन्हें जाना भी पड़ेगा।

सितंबर १९८५ में नारायण दत्त तिवारी से कार्यभार लेकर मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठने वाले वीर बहादुर सिंह को इन पौने तीन वर्षों में अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। धर्म में अटूट आस्था रखने वाले, हनुमान भक्त, वीर बहादुर सिंह, संकट मोचन का नाम लेकर हर बड़े संकट से तो उबर गये, लेकिन उपचुनाव जैसे साधारण से संकट के समय वह गच्चा खा गये। बातचीत में ठेठ पुरबिया, दिल के साफ, सांवले-सलोने वीर बहादुर में न तो अंग्रेजीदां लोगों जैसी हेकड़ी है और न चटक-मटक। बैठे-बैठे दोनों पैर उठाकर सोफे पर पलथी मार लेना या फिर बात करते-करते सोफे पर ही अधलेटे हो जाना उनकी आदत है। खाने-पीने का उन्हें कोई विशेष शौक नहीं है। लाई-चना से लेकर तंदूरी चिकन तक वह प्रेम से खाते हैं। मदिरा तो दूर-पान, सिगरेट और तंबाकू से भी उनका कोई वास्ता नहीं है।

महिलाओं से उन्हें परहेज है। कुछ पत्रकारों से तो एक बार उन्होंने यहां तक कह दिया था, "जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो अपने सरकारी दफ्तर को गंगाजल छिड़कवाकर पवित्र कराया था, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले तक खूबसूरत महिलाएं अपना काम कराने वहां आती थीं और मनचाहा आदेश कराकर चली जाती थीं। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने अपने कार्यालय में 'वैसी महिलाओं' के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।" बाद में एक अन्य पत्रिका से उन्होंने कहा था, "मैं महिलाओं की 'कंपनी' से दूर रहता हूं। मेरे दिल में महिलाओं के प्रति बड़ी इज्जत है। मैं उनमें मां, बहन और बेटी का रूप देखता हूं।"

वीर बहादुर को खाली बैठकर गप्पें मारने में काफी मजा आता है। उनकी इच्छा रहती है कि ज्यादातर लोग उनके पास बैठकर उनकी 'हां-हुजूरी' करें। यही वजह थी कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में चापलूसों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी।

विपक्षी दलों के साथ-साथ पत्रकारों को पटाकर रखने में वीर बहादुर को महारत हासिल थी। जो पत्रकार, सिंचाई मंत्री वीर बहादुर सिंह को प्रदेश का भ्रष्टतम मंत्री लिखते नहीं अघाते थे, वही उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनका खूब गुणगान करते रहे। वीर बहादुर को कार्यकर्ताओं की मानसिकता की पूरी समझ थी। हर विधायक की 'कीमत' (सिफारिश-पत्र) उन्हें मालूम थी, चाहे वह उनकी पार्टी का रहा हो या विपक्ष का। वह जब तक मुख्यमंत्री रहे, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को हैसियत में रखा। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि मंत्रियों में कौन उनका 'लायल' है और कौन खुड़पेंची।

सीधे-सादे, ग्रामीण-से दिखने वाले वीर बहादुर, राजनीतिक हथकंडों में किसी से पीछे नहीं रहे। वह खुले आम कहते हैं, "पार्टी मीटिंगों में दरी बिछाने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक, जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहीं बहुत से पाठ दूसरों को भी पढ़ाये हैं।" वीर बहादुर कोई बात दिल में नहीं रखते। किसी से नाराज हुए, तो झट सबके सामने कह दिया। २४ जून को जब राजभवन से इस्तीफा देकर वह निकले, तो अपनी कार में एक पत्रकार और एक सांसद की उपस्थिति में उन्होंने मुझसे कहा, "यह सब नाटक हो रहा है। तिवारीजी मुझे हटवाना चाहते थे, उनकी चाल सफल हो गयी है। दिल्ली में मेरी खिलाफत फोतेदार, (गुलाम नबी) आजाद और बख्शवत्त सब मिलकर कर रहे थे।" वीर बहादुर में एक खास आदत है। जिससे बदला लेना होता है, उसके लिए वह मौके की तलाश करते हैं। राजनीतिक दुश्मन के पीछे खुद न पड़कर दुश्मन को दुश्मन से लड़वा देते हैं और खुद दूर से तमाशा देखते रहते हैं।

इस राजनीतिक कला के कारण अकसर उन्हें 'उस्ताद' और 'तिकड़मी' जैसे फतवे मिलते रहे हैं। लेकिन स्वयं वीर बहादुर ने न तो अपने को कभी उस्ताद माना और न तिकड़मी। वह कहते हैं, "न मैं उस्ताद हूं न तिकड़मी। मैं तो पार्टी का अदना-सा कार्यकर्ता हूं। अपने नेता राजीव गांधी का हुक्म मानता हूं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बन जाओ, बन गया। आदेश हुआ इस्तीफा दे दो, दे दिया। जैसे मुख्यमंत्री बना था, वैसे ही जा रहा हूं।"

मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफा देने और केंद्रीय संचार मंत्री बनने के बाद 'माया' ने वीर बहादुर से लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश :

माया : *जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन से प्रेस और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गयी थी कि आपकी सरकार अब गयी तब गयी, ऐसे में आप पिछले बीस सालों में बने सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का रिकार्ड तोड़कर १००५ दिनों तक कैसे कुरसी पर बने रहे?*

वीर बहादुर सिंह : यह कोई नयी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, इसी तरह का माहौल लोग बना देते हैं। यह पिछले बीस सालों से हो रहा था। लेकिन इधर माहौल बदला है। पार्टी के सारे लोग एकजुट होकर राजीव गांधी के साथ हैं। उनके लिए हर तरह की कुरबानी देने को तैयार हैं। यही वजह थी कि यहां पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं हुई। सभी का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा था। जो लोग पार्टी में फूट की बात करते थे, उन्हें या तो हमारी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं थी या फिर वे जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते थे।

माया : *लोग कहते हैं कि आप मौका देखकर काम करते थे। जिन अरुण नेहरू ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, मौका देखते ही आपने उनसे मुंह मोड़ लिया।*

सिंह : यह सरासर गलत है। जो लोग इस भ्रम में थे कि मैं अरुण नेहरू का आदमी हूं, उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं। मैं तो शुरू से ही इंदिराजी और संजयजी के साथ था। उन्हीं की कृपा से मुझे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया। संजयजी की मुझ पर विशेष कृपा थी। अरुण नेहरू १९८० में पार्टी में आये, तब मैं 'कैबिनेट मिनिस्टर' था। इंदिराजी ने ही मुझसे कहा था, "नेहरू को रायबरेली से चुनाव जितवाना है।" उस समय इंदिराजी दो स्थानों से चुनी गयी थीं—मेडक और रायबरेली से। रायबरेली की सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अपने स्थान पर उन्होंने अरुण नेहरू को चुनाव लड़वाया था। मैंने उस समय अरुण

हरू की काफी मदद की थी। अगर कोई यह कहता है कि अरुण नेहरू ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, तो वह भ्रम में है। राजीवजी ने शुरू से लेकर आज तक मुझ पर जो विश्वास किया, उसी के कारण मैं मुख्यमंत्री बना और आज संचारमंत्री भी उन्हीं की कृपा से हूं। राजीवजी के अलावा किसी दूसरे की कोई हैसियत नहीं थी, जो मुझे मुख्यमंत्री बना देता। जो लोग कभी अरुण नेहरू को लीडर समझते थे, वह भ्रम में थे। अरुण नेहरू कभी लीडर नहीं रहे। लीडर हैं—राजीव गांधी, कांग्रेस के लीडर... हम सबके लीडर...।"

माया: ***अरुण नेहरू के बारे में आपकी राय?***

सिंह: वह बहुत दगाबाज आदमी हैं। जो भी आदमी हमारे नेता राजीव गांधी के खिलाफ काम करे, पार्टी की नीतियों की बुराई करे, जो पार्टी और लीडर को कमजोर करने का काम करे, वह हमारे लिए सबसे खराब आदमी है। ऐसे आदमी से मैं नफरत करता हूं।

माया: ***आम चर्चा है कि विरोधी दल के लोगों को आपने 'पटा' रखा था। अपनी पार्टी से ज्यादा आप विरोधी दल के लोगों को महत्व देते थे।***

सिंह: मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री था। जनता का मुख्यमंत्री था। जैसे अपनी पार्टी के लोगों के काम करता था, वैसे विरोधी दल वालों के काम करता था। लेकिन मैं किसी का कोई गलत काम नहीं करता था। जो काम नहीं हो सकता था, मना कर देता था। पब्लिक के हर आदमी और एमएलए को बराबर का महत्व देता था।

माया: ***इन एक हजार पांच दिनों के मुख्यमंत्रित्वकाल में आपकी सफलता क्या रही?***

सिंह: सफलता कम नहीं रही। बीस सूत्री कार्यक्रम में हम तीसरे साल भी 'फर्स्ट' आये। हमारे कर्मचारियों ने, अफसरों ने, जनता ने और पार्टी के लोगों ने प्रयास करके उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी। पंचवर्षीय योजना में विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, हमने उन्हें समय से पहले पूरा किया। कुछ में तो हम निर्धारित लक्ष्य से आगे पहुंचे। पिछड़े वर्ग के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में हमें ज्यादा सफलता मिली। हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं थीं। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व सूखा, राज्यकर्मचारियों के आंदोलन, किसान आंदोलन और राम-जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद विवाद का सामना किया तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाये। इस दौरान प्रदेश कर्मचारियों में अधिक अनुशासन आया और नयी कार्य संस्कृति का जन्म हुआ। कानून और व्यवस्था मेरे शासनकाल में बहुत अच्छी रही। पूरे प्रदेश में अमन चैन रहा।

माया: ***लोग आरोप लगाते हैं कि राम-जन्मभूमि का ताला आपने खुलवाया था। जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद विवाद आप इसलिए बनाये रखना चाहते थे, ताकि माहौल गरम रहे और आप कुरसी पर टिके रहें।***

सिंह: ताला हमने नहीं, अदालत के आदेश पर खुला था। हम इस विवाद को हल करना चाहते थे। इसके बारे में बात चल रही थी। इसे हल करने के दो ही रास्ते हैं—या तो इसे अदालत से तय किया जाये या फिर दोनों तरफ से बड़े और गंभीर लोग आपस में बैठकर तय करें। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। ताला खुलने के बाद जब लोगों ने रथ चलाना चाहा, तो हमने चलाने नहीं दिया।

माया: ***जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, तब आपने अचानक पद से इस्तीफा क्यों दे दिया?***

सिंह: मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। राजीवजी ने कहा कि मेरी जरूरत दिल्ली में है। उन्होंने मुझे राज्य से केंद्र में आने का निर्देश दिया, और मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं जैसे इस पद पर आया था, वैसे ही चला गया।

माया: ***लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उपचुनावों में पार्टी की हार के कारण आपको हटाया गया है?***

सिंह: मैं इसके पहले ही कह चुका हूं कि उपचुनाव का कोई असर नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में तो कोई उपचुनाव नहीं था, वहां भी नेतृत्व-परिवर्तन हुआ है।

माया: ***लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षक संतोष मोहन देव ने प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें हार के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया गया था।***

सिंह: उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब यह खबर अखबारों में छपी, तो दिल्ली में गोपीनाथ दीक्षित ने संतोष मोहन देव से बात की थी। देव का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी।

माया: ***आम चर्चा है कि आपको मुख्यमंत्री-पद से हटवाने के लिए दिल्ली में गुलाम नबी आजाद, मोहसिना किदवई और माखनलाल फोतेदार काफी दिनों से प्रयत्नशील थे। उपचुनाव के परिणामों के कारण उन्हें मुद्दा मिल गया?***

"अगर कोई यह कहता है कि अरुण नेहरू ने मुझे मुख्य मंत्री बनाया था, तो वह भ्रम में है। राजीवजी ने शुरू से लेकर आज तक मुझ पर जो विश्वास किया, उसी के कारण मैं मुख्यमंत्री बना और संचार मंत्री भी उन्हीं की कृपा से हूं।"

सिंह: अब इन सब बातों में क्या रखा है? अब तो मैं मुख्यमंत्री पद से हट ही गया हूं।

माया: ***क्या आप समझते हैं कि पार्टी के कुछ लोग नारायणदत्त तिवारी को दिल्ली से हटवाना चाहते थे, वह अपनी मुहिम में सफल हो गये हैं?***

सिंह: हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। इसमें कौन क्या चाहता है, सबके मन की बात मैं कैसे जान सकता हूं? मैं तो बस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाईकमान ने जैसा निर्देश दिया, मैंने वैसा ही काम किया। शायद हाईकमान ने यही महसूस किया कि दिल्ली में मेरी ज्यादा जरूरत है।

माया: ***राजा ने तो कहा है कि आप उपचुनाव में राजीव गांधी के निर्देश पर बेईमानी नहीं करा पाये, इसलिए पद से हटा दिये गये।***

सिंह: क्या गढ़वाल के चुनाव में बहुगुणा के खिलाफ बेईमानी कराने के लिए उनसे (राजा से) किसी ने कहा था? उस समय वह बेईमानी नहीं करा पाये थे, तो क्या हटा दिये गये थे? मेरे इस्तीफे का उपचुनावों के नतीजे से कोई संबंध नहीं है।

माया: ***तीनों उपचुनावों में आपके हिसाब से पार्टी की हार के क्या मुख्य कारण थे?***

सिंह: तीनों जगह अलग-अलग कारण थे। छपरौली में हम आज तक नहीं जीते थे। वह विपक्ष की ही सीट थी। ८ जून को वहां गोलीकांड हो गया था। टिकैत फैक्टर ने भी वहां असर डाला है। टांडा में मतदान से दो दिन पूर्व जातिवाद चल गया। हमारा कंडीडेट मुस्लिम था, लेकिन मुसलमानों ने उसे वोट नहीं दिया। वे मुस्लिम मजलिस के साथ हो गये। इलाहाबाद में प्रत्याशी के चयन में विलंब और संगठन की कमजोरी से हम हारे। इलाहाबाद में पराजय के कुछ और भी कारण थे, उनका जिक्र करना अब ठीक नहीं है।

माया: ***राजा के बारे में आपकी राय?***

सिंह: वह अवसरवादी हैं, महत्वाकांक्षी हैं। वह हमेशा ऊपर से अपनी इमेज बनाने में लगे रहते हैं, जबकि अंदर से निहायत बेईमान हैं। वह जनता के लिए नहीं, हमेशा अपने लिए काम करते हैं। इलाहाबाद के चुनाव में क्या-क्या झूठ बोला। वह स्वार्थी आदमी हैं, विपक्ष का एक नेता भी उनके साथ बैठ नहीं सकेगा।

माया: ***कुछ और कहना चाहेंगे?***

सिंह: हां, एक बात याद दिलाना चाहूंगा। जब तिवारीजी ने इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में काम करने का कोई माहौल नहीं है, यहां लोग काम के बजाय गुटबंदी ज्यादा करते हैं। मैंने इन पौने तीन सालों में उत्तर प्रदेश में न केवल काम का माहौल बनाया है, वरन् राज्य को समस्या रहित करके जा रहा हूं।

—अजय कुमार

का भी काम उन्हें सौंपा जाता, वह करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते थे। संजय के अंतरंग दोस्तों में एक अकबर अहमद डम्पी आज भी कहते हैं, "वीर बहादुर, संजय गांधी के दोस्तों के लिए शराब, बर्फ और सोडे का इंतजाम भी कर देते थे। मीट-मुर्गा तो वह खुद ही लेकर आते थे। उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी 'सेवा' करने वाला वह आदमी कभी इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बन जायेगा।" इसीलिए २४ सितंबर, १९८५ को इंका विधायक दल की बैठक में वीर बहादुर जब 'सर्वसम्मति' से नारायण दत्त तिवारी की जगह नेता चुन लिये गये, तो सब हैरत में रह गये।

काम का माहौल : नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री की कुरसी छोड़ने के बाद बड़े अफसोस के साथ कहा था, "उत्तर प्रदेश में काम करने का कोई माहौल नहीं है। यहां तो पार्टी में ही लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं।" मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठते ही वीर बहादुर ने घोषणा की, "मैं उत्तर प्रदेश में काम की संस्कृति (वर्क कल्चर) पैदा करूंगा।" इसी मुहिम के तहत सवा दस बजे सचिवालय का गेट बंद किया जाने लगा। गेट बंद करने के नियम का इतनी सख्ती से पालन शुरू हुआ कि एक दिन स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी को भी गेट के बाहर से लौटना पड़ा। गेटबंदी के साथ ही गिरोहबंदी अध्यादेश भी लागू किया गया। जिसमें सफेदपोश अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया था।

वीर बहादुर ने दूसरा मोर्चा, भ्रष्टाचार, निकम्मेपन के खिलाफ लगाया। इस मोर्चे के पहले शिकार बाराबंकी और सीतापुर के जिलाधिकारी हुए। इसके बाद लगभग हर दिन मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी और अपराधियों के विरुद्ध हो रही कार्यवाही की सूचना अखबारों में देनी शुरू कर दी।

वीर बहादुर ने तीसरा निशाना प्रशासनिक सुधार की तरफ लगाया। विभिन्न विभागों और निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए धड़ाधड़ समितियां बनीं। इन कमेटियों को दस दिन से लेकर एक महीने के अन्दर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। वीर बहादुर की इस तेजी को देखकर कुछ लोगों ने उसी समय आशंका व्यक्त की थी कि यह ठीक उसी तरह हो रहा है, जैसे किसी थाने में जब कोई घाघ दरोगा आता है, तो पूरे हलके में तहलका मच जाता है। जगह-जगह चर्चा शुरू हो गयी थी कि वीर बहादुर जमीन के आदमी हैं, इसलिए प्रदेश का कायाकल्प कर देंगे। लेकिन जल्दी ही असलियत सामने आने लगी।

कलई खुलने लगी : जिन वीर बहादुर सिंह ने १५ मिनट देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित करने का आदेश दिया था, वही खुद सरकारी कार्यक्रमों और मंत्रिमंडल की बैठकों में एक-एक घंटे देर से पहुंचने लगे। यही नहीं, सप्ताह में चार-चार, पांच-पांच दिनों तक लखनऊ से गायब रहकर दिल्ली में 'गणेश परिक्रमा' करने लगे। सरकारी विमान को तो उन्होंने टुटही साइकिल की तरह जोतना शुरू कर दिया था। सिर्फ अप्रैल १९८६ से अगस्त १९८७ के बीच सरकारी वायुयानों के ईंधन और मरम्मत पर ६५ लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गये थे। यह सिलसिला उनके मुख्यमंत्री-पद से हटने तक बदस्तूर जारी रहा। गिरोहबंद अध्यादेश की धज्जियां तो उनके अपने ही जिले गोरखपुर में उड़ गयीं। परोक्ष रूप से जिन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए यह अध्यादेश लाया गया था, गोरखपुर के वह माफिया सरगना खुले आम घूमते रहे। यह अध्यादेश कुछ ही दिनों में टांय-टांय फिस हो गया।

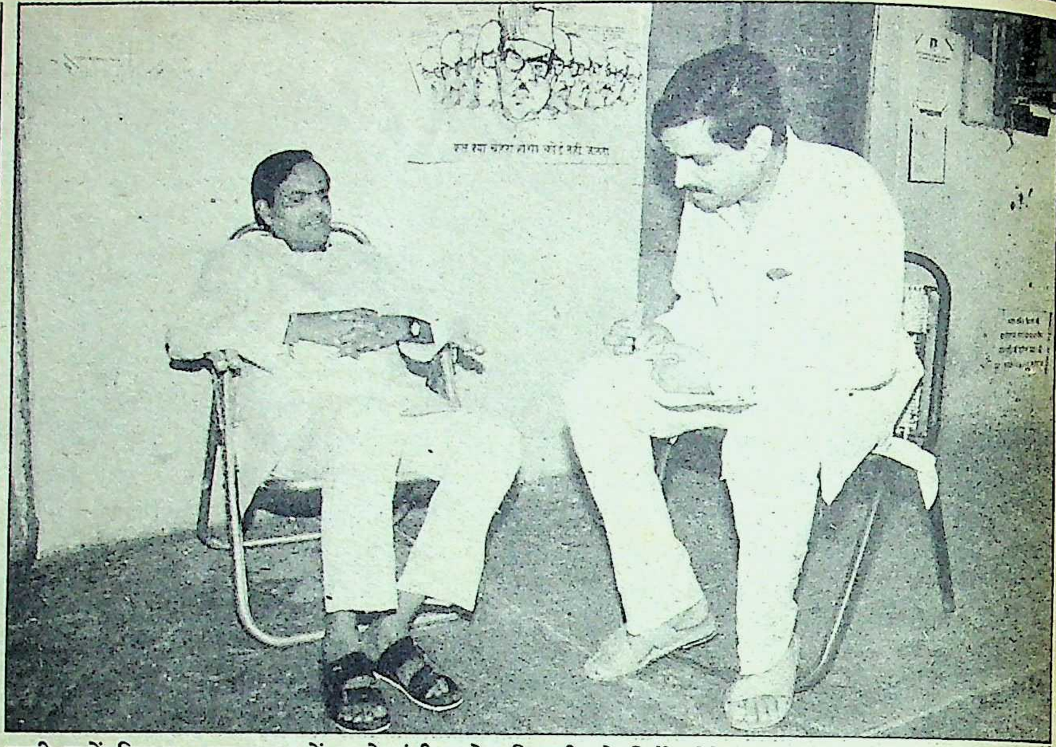

सारी चालें विफल : इलाहाबाद में अपने मंत्री प्रमोद तिवारी को निर्देश देते हुए वीर बहादुर

वीर बहादुर की भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम भी कुछ ही दिनों में औंधे मुंह जा गिरी। लोगों को शुरू से ही इस बात पर आश्चर्य था कि मुख्यमंत्री सिर्फ छोटे कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्यवाही क्यों कर रहे हैं, बड़े मगरमच्छों पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? धर्मसिह रावत के प्रकरण ने तो भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान की पोल ही खोल दी थी। रावत, शहरी भूमि हदबंदी निदेशालय में निदेशक थे। जांच पड़ताल से उन्हें पता चला कि विभाग की ८२३२ फाइलें गायब हैं। इन फाइलों को गायब कर करोड़ों रुपए मूल्य की हजारों एकड़ जमीन पर कुछ बड़े लोगों (मंत्री से लेकर आईएएस अफसरों तक ने) नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया था। विभाग के एक अधिकारी संतबली सिद्धार्थ ने १९८३ में इस हेराफेरी की सूचना सरकार को दे दी थी। लेकिन इस ओर ध्यान देने के बजाय शासन ने सिद्धार्थ को ही स्थानांतरित कर दिया।

लेकिन जब यह मामला विधानसभा में उठा, तो वीर बहादुर ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया। जांच से फाइलों के गायब होने की पुष्टि हो गयी। इसी निदेशालय के एक अन्य अधिकारी आरएन भाटिया ने एक और सनसनीखेज रहस्योद्‌घाटन कर दिया। प्रदेश के कुछ बड़े अफसरों ने मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) इनायत हबीबुल्ला और एक बिल्डर्स हलवासिया से सांठगांठ कर उन्हें लखनऊ में महंगे इलाके हजरतगंज में एक जमीन पर बहुमंजिली व्यावसायिक इमारत बनाने की छूट दे दी थी। यह जमीन हबीबुल्ला के भाई की थी जो पाकिस्तान चले गये थे। शत्रु संपत्ति कानून के मुताबिक यह जमीन सरकार को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हबीबुल्ला की पत्नी बेगम हमीदा हबीबुल्ला इंका की पूर्व सांसद थीं तथा इस घटनाक्रम के दौरान उनके पुत्र वजाहत हबीबुल्ला प्रधानमंत्री सचिवालय में तैनात थे, इस कारण बड़े अफसरों ने उन्हें हर तरह की छूट दे दी। यही नहीं 'बिल्डर्स' से अफसरों ने उचित कीमत भी वसूली। उन्नीस आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को इस इमारत में कौड़ियों के भाव फ्लैट दिये गये। इस मामले में करीब पांच करोड़ का घोटाला हुआ था। इन सब घोटालों की शिकायतें प्रधानमंत्री तक भी पहुंचीं, लेकिन वीर बहादुर सुरक्षित रहे।

विवादास्पद कार्य और बदनामी : राजनीतिक मोहरे बिठाने और उठापटक की राजनीति में माहिर वीर बहादुर सिंह प्रशासनिक मामलों में भी ज्यादा सफल नहीं रहे। इसकी एक खास वजह यह थी कि कुछ चाटुकार अफसर और टुटपुंजिया नेता वीर बहादुर को हर समय घेरे रहते थे। यही वजह थी कि अनेक विवादास्पद कार्यों के कारण इन पौने तीन वर्षों में वीर बहादुर की काफी बदनामी हुई। ऐसा ही एक मामला 'हार्टिको' का था। इस निगम के पूर्व निदेशक ने निगम में करीब तीन सौ लोगों की नाजायज ढंग से नियुक्ति की थी। जिन लोगों को नियुक्तियां मिली थीं, उनमें निगम के अध्यक्ष रामपलट चतुर्वेदी के दामाद विनोद कुमार

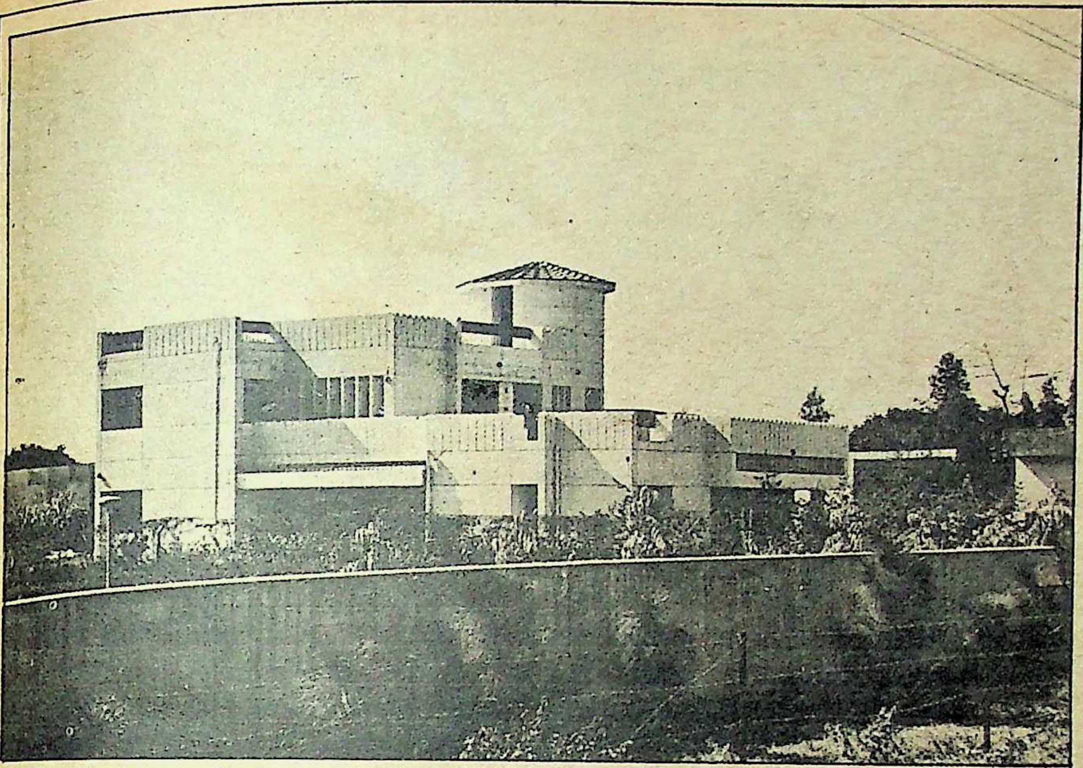

विवादास्पद : देहरादून में वीर बहादुर की कथित कोठी

मिश्र और कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह के भतीजे एमके सचान भी थे। विभागीय आडिट में पाया गया कि 'हार्टिको' के कई बड़े अफसरों ने फलों की खरीद और डिब्बा बंद जूस की बिक्री में लाखों रुपयों की गड़बड़ी की थी। कर्मचारी यूनियन ने अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की एक लम्बी सूची मुख्यमंत्री और कृषिमंत्री को दी थी, लेकिन उसकी जांच के बजाय वीर बहादुर ने हार्टिको के प्रबंध निदेशक को एक बड़े विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद सौंप दिया।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र देव मिश्र का मामला तो और भी शर्मनाक था। वहां के सांसद केदारनाथ सिंह ने मिश्र पर तमाम आरोप लगाये थे। वीर बहादुर, सांसद और उपाध्यक्ष की लड़ाई मुस्कराते हुए देखते रहे। बाद में दिल्ली से दबाव डलवाकर केदारनाथ सिंह उपाध्यक्ष को हटवाने में सफल हो सके। भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने का सबसे ताजा उदाहरण खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक वीपी मिश्र और राज्य सेतु निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ब्रजेंद्र सिंह का है। दोनों के खिलाफ विधानसभा में मामले उठे थे। मिश्र को सतर्कता विभाग की जांच तक से बचा लिया गया और सिंह के तो सेवा-काल में तीन बार वृद्धि की। फल एव उद्यान निदेशक जंगबहादुर सिंह के बारे में स्वयं वीर बहादुर ने कई बार यह कहा था कि 'वह ठीक आदमी नहीं है', लेकिन इसके बावजूद कृषिमंत्री के कहने पर उनका सेवाकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया था। वीर बहादुर ने ऐसे दर्जनों अफसरों के सेवाकाल में वृद्धि की, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। दूसरी ओर आईएएस अधिकारी पंकज कुमार को परिवहन निगम से इसलिए हटा दिया गया था कि वह इंका की रैलियों के लिए निगम की बसें नाजायज ढंग से देने को तैयार नहीं थे। बाद में ऊब कर पंकज कुमार ने प्रशासनिक सेवा से ही इस्तीफा दे दिया।

सहकारिता विभाग के एक अफसर बीएस सक्सेना का तबादला एक क्लर्क के कहने पर कर दिया गया। इस क्लर्क के विरुद्ध लाखों रुपयों की हेराफेरी करने का मामला पुलिस में दर्ज था। सक्सेना ने उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की, तो क्लर्क ने सहकारिता मंत्री अरुण कुमार सिंह से कहकर सक्सेना का ही तबादला करा दिया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में खाद्य और दवा नियंत्रक के पद पर एमसी बिंदल को नियुक्त करके लोकसेवा आयोग का भी मखौल उड़ाया गया। आयोग ने इस पद के लिए रामचन्द्र सिंह का चयन किया था। बिंदल का नाम प्रतीक्षा सूची में था।

वीर बहादुर ने अफसरों की गुटबंदी बढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। उनके मुख्यमंत्री बनने के पूर्व तक प्रदेश के ज्यादातर विभागों में ब्राह्मण अफसरों का बालबाला था। मुख्यमंत्री बनते ही वीर बहादुर ने ब्राह्मण अफसरों की काट शुरू कर दी। उनमें से कई तो, प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में चले गये। अफसरों के बीच चल रही ब्राह्मण हरिजन धुरी को तोड़कर वीर बहादुर ने हरिजन-ठाकुर लाबी तैयार कर दी थी।

अपनी इस पैंतरेबाजी से वीर बहादुर को राजनीतिक लाभ भले ही मिला हो, लेकिन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में नौकरशाही बेलगाम और पुलिस अत्याचारों में असाधारण वृद्धि हुई। पुलिस का अहंकार कितना बढ़ गया था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ के एक दरोगा ने तो गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित के बेटे विजय दीक्षित की ही जमकर पिटाई कर दी थी।

दरअसल वीर बहादुर के पास प्रशासनिक कार्य देखने का समय ही नहीं था। उनका सारा प्रशासनिक कार्य सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर तक के अधिकारी ही देखते थे। इनमें कई तो यह शिकायत करते घूमते थे कि एक-एक फाइल मुख्यमंत्री को दिखाने में हफ्तों लग जाते हैं। मुख्यमंत्री के पास सचिवों-अनुसचिवों की फौज के अलावा अधिकृत रूप से सात सलाहकार भी थे। इन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन संसदीय सलाहकार को छोडकर शायद ही कोई सलाहकार कभी सलाह देने के लिए वीर बहादुर के करीब देखा गया हो।

समस्याओं की खेती : वीर बहादुर दिल्ली में दरबार लगाने में माहिर हो चुके थे। अपनी चतुराई के कारण ही वह काफी दिनों तक दिल्ली दरबार की निगाह में कमजोर या असफल साबित नहीं हुए। वह पहले समस्याओं को जन्म देते थे, फिर उन्हें बढ़ाने के लिए खाद और पानी डालते थे। अंत में समस्या को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा देते थे कि दिल्ली दरबार को मुख्यमंत्री की 'बहादुरी' की दाद देनी पड़ती थी। वीर बहादुर की कुटिल राजनीति का खुलासा फरवरी १९८६ में राम जन्मभूमि का ताला खोले जाने के समय हुआ था। कहते हैं कि वीर बहादुर की सलाह पर ही फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी इन्दुकुमार पांडेय ने अदालत में ताला खोलने के पक्ष में बयान दिया था और पुलिस अधीक्षक कर्मवीर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन देकर ताला खुलवा दिया था।

इसी के बाद दिल्ली दरबार यह सोचकर खुश हो गया था कि वीर बहादुर ने इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान निकालने के साथ ही बहुसंख्यक वर्ग को इंका के पक्ष में कर लिया है। लेकिन इसके बाद दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने वीर बहादुर की कुरसी बचाने में मदद की। ताला खुलने के बाद ३७ जिलों में छोटे-बड़े दंगे हुए थे। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक इन दंगों में १८१ लोगों की जान गयी थी। इन घटनाओं से वीर बहादुर बदनाम जरूर हुए थे, लेकिन दिल्ली दरबार को बराबर यह डर लगा रहता था कि दंगों के कारण अगर वीर बहादुर को हटाया गया, तो कहीं वह एक हिन्दू नेता के रूप में स्थापित होकर दरबार के लिए ही सिरदर्द न बन जायें। इन दंगों के जरिये वीर बहादुर ने अपना राजनीतिक स्वार्थ भी बखूबी सिद्ध कर लिया। बड़ी चालाकी से उन्होंने मेरठ के दंगे की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई पर थोप दी थी। एक समय में तो मोहसिना की यह हालत हो गयी थी कि उनका मुख्यमंत्री की कुरसी की ओर देखना तो दूर, मेरठ में घुसना ही दूभर हो गया था।

महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में मेरठ के किसान आन्दोलन ने जब विकराल रूप धारण कर लिया, तो वीर बहादुर ने दिल्ली दरबार को समझाया कि इससे कांग्रेस को ही फायदा है, क्योंकि टिकैत के गैरराजनीतिक आन्दोलन से जाटों के बीच लोकदल की पकड़ ढीली पड़ जायेगी। लिहाजा इस आन्दोलन का तेज होना कांग्रेस के हित में है। टिकैत के आन्दोलन के जवाब में वीर बहादुर ने लखनऊ में विशाल रैली करा दी थी।

हरनही से दिल्ली तक

वीर बहादुर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद १००५ दिनों तक मुख्यमंत्री की कुरसी पर कैसे जमे रहे, इस संबंध में लोग तरह-तरह कीं बातें करते हैं। कोई कहता है कि उन्होंने सोनिया गांधी का पल्लू थाम रखा था, तो कोई उन्हें राजीव गांधी का विश्वासपात्र बताता है। लेकिन इस बारे में वीर बहादुर कहते है, ''मैं नेता नहीं, कार्यकर्ता हूं, मेरी सफलता का यही राज है।''

दरअसल राजनीतिक दांवपेंच और तिकड़म के माहिर वीर बहादुर की राजनीतिक यात्रा का एक लंबा इतिहास है। गोरखपुर के अत्यंत पिछड़े गांव हरनही में एक गरीब कृषक रघुनंदन सिंह के घर १९३५ में जन्मे वीर बहादुर सिंह को एमए तक पंढ़ाने-लिखाने और राजनीति में दीक्षित करने का श्रेय उनके बहनोई रामअवध सिंह को जाता है।

उनके बहनोई उन दिनों गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चूंकि वीर बहादुर जिला कांग्रेस कार्यालय के ही एक कमरे में रहते थे, इसलिए शिक्षा-ग्रहण के साथ-साथ वह युवक कांग्रेस में भी सक्रिय हो गये। यह १९६०-६२ का दौर था। उस समय प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में दो गुट आमने-सामने थे। एक का नेतृत्व चंद्रभानु गुप्त कर रहे थे, तो दूसरे की बागडोर कमलापति त्रिपाठी के हाथ में थी। हेमवती नंदन बहुगुणा, कमलापति के खास सलाहकार थे।

चंद्रभानु गुप्त से टक्कर लेने के लिए जब बहुगुणा ने युवा कांग्रेसियों की एक टीम बनायी, तो पार्टी कार्यालय में नेताओं की सेवा करने वाले वीर बहादुर को भी उसमें शामिल किया गया। यहीं से वीर बहादुर को अपनी 'कार्य कुशलता' दिखाने का मौका मिला। जल्दी ही वह बहुगुणा के विश्वासपात्र हो गये। नतीजतन त्रिपाठी-बहुगुणा गुट ने चंद्रभानु गुप्त के विरोध के बावजूद वर्ष १९६७ में वीर बहादुर को पनियारा (गोरखपुर) से विधानसभा का चुनाव लड़वाया। भारी बहुमत से चुनाव जीत कर वीर बहादुर ने प्रदेश की राजनीति में प्रवेश पा लिया। अपनी सज्जनता, भोलेपन और 'जो जैसा हो, उसे स्वीकार लो' की नीति पर चलते हुए वीर बहादुर दो वर्षों में ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की नजर में चढ़ गये। वर्ष १९६९ के मध्यावधि चुनाव में वह दुबारा विधायक बन गये।

इसी दौरान वीर बहादुर ने बहराइच के पूर्व सांसद सरदार जोगेंदर सिंह के यहां हाजिरी बजानी शुरू कर दी थी। सरदारजी के यहां ओम मेहता का भी आना-जाना था। उन दिनों दिल्ली दरबार में ओम मेहता की तूती बोलती थी। सरदारजी ने एक दिन ओम मेहता से वीर बहादुर की सिफारिश करते हुए कहा था, ''यह बहुत गरीब आदमी है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से एमएलए बना है, अपने बहुत विश्वास का आदमी है।''

बस, इसी के बाद वीर बहादुर, ओम मेहता की 'सेवा' में लग गये थे। नतीजतन जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिदल और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनी, तो १९ अप्रैल, १९७० को वीर बहादुर सिंह उपमंत्री बनाये गये। कहते हैं कि उन्हें ओम मेहता की सिफारिश पर 'हरिजन कोटे' में 'एडजस्ट' किया गया था, क्योंकि ओम मेहता को यह भ्रम था कि वीर बहादुर हरिजन हैं। इसके बाद वीर बहादुर ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

वीर बहादुर को सत्ता केंद्र के निकट जाने का सुनहरा मौका तब मिला जब वह इमरजेंसी के दौरान अमेठी में संजय गांधी के करीब आये। उन्होंने श्रमदान शिविरों आदि में ऐसी निष्ठा और मेहनत से काम किया कि संजय गांधी के बहुत नजदीक आ गये। वर्ष १९८० आते-आते वीर बहादुर की महत्वाकांक्षा काफी ऊपर उठ चुकी थी। तब तक वह कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य भी बन गये थे। यही वजह थी कि १९८० के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वीर बहादुर ने जहां अपने तमाम प्रियपात्रों को टिकट दिलाये, वहीं दर्जनों नापसंद लोगों के टिकट कटवा भी दिये थे। उस समय पार्टी टिकट पर विधानसभा में जीतकर पहुंचे ३०९ विधायकों में वीर बहादुर समर्थकों की संख्या लगभग २०५ थी। अगर विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चुनाव होता, तो वीर बहादुर उसी समय मुख्यमंत्री बन गये होते। लेकिन् संजय सिंह-अकबर अहमद का गुट न तो वीर बहादुर को चाहता था और न ही नारायण दत्त को। इसीलिए उनके प्रयास से इंका विधानमंडल दल ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि संजय गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाये। नतीजतन श्रीमती गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और दिल्ली से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश भेज दिया।

वीर बहादुर के जीवन में यह पहला राजनीतिक झटका था। लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह समझ गये थे कि दिल्ली दरबार में अपनी मजबूत लाबी बनाये और प्रदेश में अपने राजनीतिक विरोधियों की काट किये बिना, वह मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। अचानक जून, १९८० में संजय गांधी के आकस्मिक निधन से वीर बह्मदुर को दूसरा बड़ा धक्का लगा, क्योंकि दिल्ली दरबार में संजय गांधी ही उनके सबसे बड़े 'गाड फादर' थे।

इसी बीच श्रीमती गांधी ने रायबरेली से रिक्त की गयी अपनी सीट से अरुण नेहरू को उम्मीदवार बनाने का निश्चय कर लिया और चुनाव में मदद के लिए वीर बहादुर को लगा दिया। वीर बहादुर की भक्ति से प्रभावित अरुण नेहरू को अपने 'भक्त' की उस्तादी की कभी पहचान नहीं हो सकी और वह वीर बहादुर के सबसे बड़े पैरोकार बन गये। अरुण नेहरू की वीपी सिंह से नहीं पटती थी, लेकिन फिर भी वह वीर बहादुर को काफी कोशिशों के बावजूद महत्वहीन नहीं कर सके। वीपी सिंह के हटने के बाद श्रीपति मिश्र और उनके बाद नारायण दत्त तिवारा की मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन धुन के पक्के वीर बहादुर ने अरुण नेहरू का हाथ नहीं छोड़ा। इसका उन्हें सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि एक-एक करके प्रदेश के दिग्गज नेता—ब्रह्मदत्त, बलराम सिंह यादव, राजमंगल पांडेय—संसद में पहुंचा दिये गये और वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश में आलाकमान के सबसे विश्वसनीय नेता बन गये। नतीजतन जब नारायण दत्त तिवारी की दिल्ली में आवश्यकता महसूस हुई, तो संजय सिंह, लोकपति त्रिपाठी आदि का दावा धरा रह गया और वीर बहादुर मुख्यमंत्री बन गये। १९८७ आते-आते वीर बहादुर को भनक लग गयी कि अब अरुण नेहरू का वजन कम हो रहा है। उन्होंने मौका देखा और झट अमिताभ बच्चन का दामन थाम लिया। साथ में कैप्टन सतीश शर्मा से भी पटरी बिठा ली। जब देखा कि नारायण दत्त तिवारी, मोहसिना

किदवई और फोतेदार का गुट भारी पड़ता है, तो उमाशंकर दीक्षित के दरबार में बढ़ते प्रभाव को देख कर, गोपीनाथ दीक्षित को अपने मंत्रिमंडल में गृहमंत्री के रूप में शामिल कर लिया और बड़े दीक्षित की कृपा प्राप्त कर ली। इधर मेरठ दंगे का ठीकरा मोहसिना कितवई के सिर पर फोड़ दिया और राजमंगल पांडेय की 'ड्राइंग रूम पालिटीशियन छवि' बना कर उनको अपने रास्ते से साफ कर दिया। संजय सिंह को कोंच-कोंच कर पार्टी से बाहर भेज दिया और अरुण सिंह के दरबार से बाहर हो जाने पर अरुण सिंह 'मुन्ना' की लाबी अपने आप कमजोर हो गयी थी।

इस बीच वीर बहादुर ने एक तीर और मार लिया था। १९८४ के लोकसभा चुनाव में वह सोनिया गांधी के काफी करीब आ चुके थे। डाक्टरों की टीम के साथ जब सोनिया गांव-गांव दवा बांटने जाती थीं, तो उनके पीछे वीरे बहादुर भी लगे रहते थे। इससे उनकी दरबार में अच्छी खासी पैठ हो गयी थी और वह चैन की बंसी बजा रहे थे। लेकिन अचानक इलाहाबाद चुनाव की गाज गिर गयी और वीर बहादुर को लखनऊ से उखड़ना पड़ा। पर यह काबिलेगौर है कि उनकी जगह लेने वाला कोई व्यक्ति लखनऊ में नहीं मिला। केंद्र से तिवारी को ही लाकर उनका उत्तराधिकारी बनाना पड़ा और स्वयं वीर बहादुर को संचार मंत्री के रूप में पुनर्स्थापित करना पड़ा।

मुख्यमंत्री की कुरसी पर इतने अधिक समय तक टिके रहने के पीछे वीर बहादुर की चालाक राजनीति के साथ-साथ उनका भाग्यशाली होना और धर्म तथा कर्मकांड में विश्वास करना भी एक कारण माना जाता है। वीर बहादुर के दाहिने हाथ में ढेर सारे कलावा (रक्षा धागे) बंधे रहते हैं। गले में छोटे रुद्राक्ष की माला रहती है। मंगलवार को संकटमोचन के सामने माथा टेकते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं। अपने गांव में उन्होंने शंकरजी का विशाल मंदिर बनवाया है। प्रत्येक नवरात्रि की अष्टमी के दिन यज्ञ करने के बाद वे मां विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु विंध्याचल अवश्य जाते हैं। गोंडा के देवीपाटन मंदिर और देवरिया के देवराहा बाबा पर उनकी अटूट श्रद्धा है। कोई उन्हें सांप्रदायिक न कहे, इसलिए वह अजमेर शरीफ पर हर वर्ष चाद्दर चढ़ाने भी नियमित रूप से जाते हैं। यही वजह है कि जब-जब उन पर संकट आया, संकटमोचन और मां भगवती से लेकर उनके भाग्य ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन इलाहाबाद के संकट से वह उबर नहीं सके।

—अजय कुमार

> वीर बहादुर ने मेरठ का किसान आंदोलन देखा और कर्मचारियों की तीन लम्बी हड़तालें वह झेल गये। बम्बई की सिनेमा हडताल ने महाराष्ट्र सरकार को तो हिलाकर रख दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ३१ दिनों तक चलने वाली सिनेमा हड़ताल को वीर बहादुर एक तमाशाई की तरह देखते रहे थे।

लड़ाओ और राज करो: दरअसल, वीर बहादुर ने समस्याओं को एक अकलमंद राजनेता के बजाय, वीरता से दूर करने की पहलवानी दिखायी, जिसका परिणाम सामने है। 'बांटो और शासन करो,' वीर बहादुर की सफलता का सबसे बड़ा राज था। इस नीति के तहत जहां उन्होंने विपक्ष को विभाजित कर दिया था, वहीं अपनी पार्टी के लोगों को भी वह आपस में लड़ाकर तमाशाई बने रहते थे। विपक्षी नेता मुख्यमंत्री के पास जो भी काम लेकर जाते थे, वह फौरन हो जाता था। नतीजतन सभी विपक्षी नेता मुख्यमंत्री से सांठगांठ के आरोप से घिर गये और अपने-अपने दल में उनकी आलोचना शुरू हो गयी थी।

ठीक यही रणनीति पार्टी के भीतर भी उन्होंने अपनायी थी। जंब अमिताभ बच्चन का बोलबाला था, तो वीर बहादुर ने श्यामसूरत उपाध्याय को अपना सबसे नजदीकी सहयोगी समझा था। एक समय में तो उपाध्याय, वीर बहादुर के 'किचन मिनिस्टर' के रूप में मशहूर हो गये थे। लेकिन अमिताभ का प्रभाव घटते ही, उन्होंने उपाध्याय की जगह इलाहाबाद की राजनीति में अशोक वाजपेयी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। लोकपति त्रिपाठी की ब्राह्मण लाबी को तोड़ने के लिए वीर बहादुर ने गोपीनाथ दीक्षित को आगे कर दिया था। वीर बहादुर हर समय यह पता लगवाते रहते थे कि किस जिले में विधायक और सांसद की चल रही है। पार्टी में विधायकों को सांसदों से लड़ाये रखने और मंत्रियों को विभागीय सचिवों से भिड़ाये रखने का गुर वीर बहादुर अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक सांसद, मंत्री और विधायक आपसी लड़ाई में फंसे रहेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री की कुरसी की ओर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा।

मेरठ की राजनीति में मोहसिना किदवई का विरोध करने के लिए वह राज्यसभा सदस्य शांति त्यागी को बराबर बढ़ावा देते थे। वाराणसी में लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध रत्नाकर पांडेय तथा आगरा में गुलाब सेहरा के खिलाफ कभी आजाद कुमार कर्दम, तो कभी कृष्णवीर सिंह कौशल को हटा देने का काम वीर बहादुर बदस्तूर करते रहे।

तिवारी पर नजर: वीर बहादुर को यह अच्छी तरह पता था कि मुख्यमंत्री-पद के दावेदार ब्रह्मदत्त को कमजोर करने के लिए नारायण दत्त तिवारी को हैसियत में रखना जरूरी है। इसके लिए उंन्होंने मौका पाते ही ऐसे हथियार का प्रयोग किया था, जिससे दिल्ली दरबार को तिवारी की 'हैसियत' का पता चल गया था। काशीपुर के उपचुनाव में वीर बहादुर वहां के एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने के लिए कह रहे थे। लेकिन चूंकि वह नारायण दत्त तिवारी का गढ़ था, इसलिए उन्होंने अपने प्रियपात्र अम्मार रिजवी को टिकट दिला दिया था। नतीजतन वीर बहादुर ने 'तटस्थ' रहने की नीति अपना ली। अपने नेता की 'तटस्थता' को देख पार्टी का एक गुट अम्मार रिजवी के खिलाफ भितरघात पर उतारू हो गया। नतीजतन अम्मार रिजवी, अकबर अहमद डम्पी से चुनाव हार गये। नारायण दत्त तिवारी ने कई दिनों तक काशीपुर में रहकर चुनाव-प्रचार किया था। अपने ही गढ़ में अपने प्रियपात्र की हार से तिवारी को व्यक्तिगत नुकसान हुआ था। जबकि उसी दौरान हुए पट्टी, राठ और हरिद्वार के दो विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव में वीर बहादुर, पार्टी उम्मीदवारों को 'किसी तरह' जिताने में सफल हो गये थे।

इसी के बाद वीर बहादुर ने नारायण दत्त तिवारी के विरोधी, केंद्रीय मंत्री कृष्णचंद्र पंत के गुट को प्रदेश में महत्व देना शुरू कर दिया। पंत का राजनीतिक दबदबा कायम करने के लिए पूरे प्रदेश में उनके पिता तथा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाने के आदेश वीर बहादुर ने दे दिये थे। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि वीर बहादुर ने अपने कुछ समर्थकों के जरिये पिछले दिनों लखनऊ और दिल्ली में बड़ी तादाद में एक पोस्टर चिपकवा दिये थे। जिनमें उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी नामक एक संस्था की ओर से यह मांग की गयी थी कि नारायण दत्त तिवारी को उप-प्रधानमंत्री अथवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाये तथा ब्रह्मदत्त को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाये। यही पोस्टर उन्होंने दिल्ली दरबार में भी पहुंचा दिया था।

अपनी कुरसी बचाये रखने के लिए दिल्ली दरबार के सामने वीर बहादुर सिंह ने किस तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह का हौवा खड़ा किया था, वह किसी से छिपा नहीं है। गोरखपुर में उनकी सभा पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें गिरफ्तार कराना तथा उनके समर्थक दो मंत्रियों—जफ़रअली नकवी और सुरेंद्र सिंह—को बरखास्त करना। इन दो घटनाओं ने विश्वनाथ प्रताप को इतना क्षुब्ध कर दिया था कि वह राजीव गांधी के खिलाफ बोलने लगे थे। इसके

पूर्व वह राजीव गांधी के खिलाफ नहीं बोलते थे। उस समय तक दोनों के बीच समझौते की संभावनाएं बाकी थीं। लेकिन वीर बहादुर ने ऐसा नहीं होने दिया।

संजय सिंह से मुक्त होने के बाद वीर बहादुर ने 'कीमत चुकाओ, समर्थन लो' की नीति अपना कर विश्वनाथ प्रताप सिंह समर्थक विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया था। विधायकों ने अपने क्षेत्र या व्यक्तिगत हित के लिए जो भी मांगा, वह उन्हें दो वर्ष के शासनकाल में पहली बार दिया गया। विधायकों से सामूहिक सौदेबाजी के तहत उनका वेतन और भत्ता चार हजार रुपए मासिक से बढ़ाकर आठ हजार कर दिया गया। इस तरह वीर बहादुर, पार्टी विधायकों को जनमोर्चा में जाने से रोकने में सफल तो हो गये थे, लेकिन ट्रेन लेट कराने अथवा सभाओं में सांप छोड़ने जैसी घटिया हरकतें कराने के बावजूद वह राजा की सभाओं में भीड़ कम करने में कामयाब नहीं हुए। इसके जवाब में लखनऊ और कानपुर में विशाल रैलियां आयोजित कर दिल्ली दरबार को यह बताने में वह जरूर सफल हो गये थे कि राजा से भी ज्यादा भीड़ वह (वीर बहादुर) इकट्ठा कर सकते हैं।

लेकिन मात खा गये: लेकिन यह भी एक विडंबना ही थी कि २४ जून की प्रातः करीब पौने ग्यारह बजे जब इलाहाबाद का किला फतह कर राजा मांडा अपने स्वागत जुलूस के साथ लखनऊ में विधानभवन के सामने से गुजर रहे थे, तो ठीक उसी समय वीर बहादुर मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफा देकर राजभवन से निकल रहे थे। उन्हें देखते ही जनमोर्चा की ओर से नारे लगने लगे, "लखनऊ को जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है।'

यह भी एक तथ्य है कि वीर बहादुर अपनी गफलत के कारण ही मात खा गये। २० फरवरी और १ मई को राजीव गांधी से सार्वजनिक रूप से 'चरित्र प्रमाणपत्र' पाकर वीर बहादुर यह सोचकर आत्मतुष्ट हो गये थे कि वह अब अगले चुनाव तक इस कुरसी पर बने रहेंगे। लेकिन मई महीने से ही वीर बहादुर के सितारे गर्दिश में आ गये थे।

१ मई को कानपुर में आयोजित श्रमिक रैली में वीर बहादुर के न चाहते हुए भी गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश सेवादल के प्रमुख जगदम्बिका पाल को प्रधानमंत्री के समक्ष भाषण के लिए आमंत्रित कर लिया था। उस समय वीर बहादुर को बहुत ही नागवार लगा था। आजाद ने यह बदला इसलिए लिया था, क्योंकि २० फरवरी की लखनऊ रैली में वीर बहादुर ने नारायण दत्त तिवारी को मंच पर न बिठाकर सौ गज दूर श्रोताओं के बीच बैठने को बाध्य किया था।

अपनी तिकड़म और कूटनीति से हर आड़े मौके पर अपने को बचाकर निकल जाने वाले वीर बहादुर सिंह इसी के बाद मुसीबत में फंसते चले गये। उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया उत्तर प्रदेश में इंका के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने। आजाद, प्रदेश की राजनीति में नारायण दत्त तिवारी और मोहसिना किदवई के खास समझे जाते हैं। मेरठ के दंगे के बाद मोहसिना और वीर बहादुर के बीच द्वेष बढ़ गया था।

> प्रधानमंत्री मेरठ पहुंच गये हैं—यह खबर वीर बहादुर को लगी, तो वह सन्न रह गये। जल्दी-जल्दी यज्ञ का समापन कराया और सरकारी विमान से मेरठ जा पहुंचे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोजा इफ्तार खतम कर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे।

आजाद ने वीर बहादुर को हैसियत में लाने के लिए इस बात का दबाव डाला कि सुशीला रोहतगी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाये। यह दबाव चार महीने पहले पड़ा था। लेकिन उस समय वीर बहादुर ने पार्टी विधायकों को उकसा कर अपना घेराव करा लिया था। फिर दिल्ली दरबार में यह खबर पहुंचवा दी थी कि विधायकों के विरोध के कारण इस समय किसी बाहरी व्यक्ति को मंत्री-पद दिलाना खतरे से खाली नहीं है।

लकिन जैसे ही श्रीमती रोहतगी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली, अगले ही दिन न चाहते हुए वीर बहादुर को उन्हें ऊर्जामंत्री बनाना पड़ा था। इसी के बाद यह चर्चा शुरू हो गयी थी कि जब सुशीला रोहतगी का दिल्ली दरबार में इतना दबाव है, तो प्रदेश में वीर बहादुर का विकल्प ढूंढ़ना आसान हो गया है।

गुलाम नबी आजाद ने इसी के बाद १६ मई को वीर बहादुर को जो झटका दिया; उससे वह अंत तक संभल नहीं पाये। जिंदगी में पहली बार वीर बहादुर ने जिस तरह का धोखा खाया था, उसका मलाल उन्हें हमेशा रहेगा। उस दिन वीर बहादुर अपने गांव हरनही (गोरखपुर) में चल रहे यज्ञ का समापन करने गये हुए थे। यह खबर गुलाम नबी आजाद को लगी, तो झट उन्होंने राजीव गांधी को मेरठ चलने के लिए तैयार कर लिया। आजाद ने प्रधानमंत्री को समझाया था कि मेरठ के मुसलमानों के बीच आप द्वारा इफ्तार करने से अल्पसंख्यकों का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़ेगा।

आजाद ने इस बात की मुकम्मल व्यवस्था कर ली थी कि प्रधानमंत्री की मेरठ यात्रा की खबर यज्ञ का समापन कर रहे वीर बहादुर तक न पहुंच सके। आनन-फानन प्रधानमंत्री को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे आजाद मेरठ पहुंच गये। साथ में मोहसिना किदवई और नारायण दत्त तिवारी भी थे।

मेरठ जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना पीएम हाउस से साढ़े चार बजे के बीच मिली थी। जिला प्रशासन ने लखनऊ में गृह सचिव को तत्काल इसकी सूचना दे दी। मुख्यमंत्री के बिना प्रधानमंत्री मेरठ पहुंच रहे हैं, यह खबर लखनऊ में मिलते ही मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग परेशान हो गये थे। यज्ञ स्थल पर कोई फोन नहीं था। 'हाट लाइन' पर गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क किया गया, तो पता चला वह भी यज्ञ स्थल पर हैं। आनन-फानन आदमी दौड़ाये गये।

प्रधानमंत्री मेरठ पहुंच गये हैं—यह खबर वीर बहादुर को लगी, तो वह सन्न रह गये। जल्दी-जल्दी यज्ञ का समापन कराया और सरकारी विमान से मेरठ जा पहुंचे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोजा इफ्तार खतम कर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे।

इसी के बाद वीर बहादुर को यह संदेह हो गया था कि गुलाम नबी आजाद, मोहसिना किदवई और नारायण दत्त तिवारी उनके पीछे पड़ गये हैं। और जब २३ मई को इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वीर बहादुर के विरोध के बावजूद सुनील शास्त्री का नाम तय हो गया, तो उनका संदेह यकीन में बदल गया। इसके पूर्व राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी वीर बहादुर समर्थक किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया था। यही नहीं, जब महाबीर प्रसाद को केंद्र में उपमंत्री बना दिया गया, तो वीर बहादुर ने काफी प्रयास किया कि बलराम सिंह यादव को प्रदेश इंका का अध्यक्ष बना दिया जाये, लेकिन उनका यह आग्रह भी ठुकरा दिया गया।

वीर बहादुर को मुख्यमंत्री-पद से हटवाने में इलाहाबाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल, नारायण दत्त तिवारी, पांचवें दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष थे। उस समय माखनलाल फोतेदार विश्वविद्यालय छात्रसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य थे। तिवारी और फोतेदार ने मोहसिना किदवई और ब्रह्मदत्त की सहायता से पिछले कुछ समय से दिल्ली में अपनी जो सशक्त लाबी बना ली थी, वीर बहादुर उस लाबी की ताकत का सही अंदाज नहीं लगा सके थे। इस लाबी को परदे के पीछे से मदद करने का काम गोपी अरोड़ा कर रहे थे जो प्रधानमंत्री के खास सलाहकार थे तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। अंत में इलाहाबाद के ही उपचुनाव ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस्ताद और तिकड़मबाज समझे जाने वाले वीर बहादुर को मुख्यमंत्री-पद से हट जाना पड़ा। लेकिन यह भी विडंबना है कि उनका उत्तराधिकारी स्वयं नारायण दत्त तिवारी को ही बनना पड़ा। वह यह तो चाहते थे कि वीर बहादुर हटें, लेकिन वह यह कतई नहीं चाहते थे कि वह केंद्र से हट कर राज्य तक सीमित हो जायें। पर हुआ वही।

—अजय कुमार

छाया: मनमोहन शर्मा, राजेन्द्र कुमार

तिवारी की लखनऊ वापसी क्यों ?

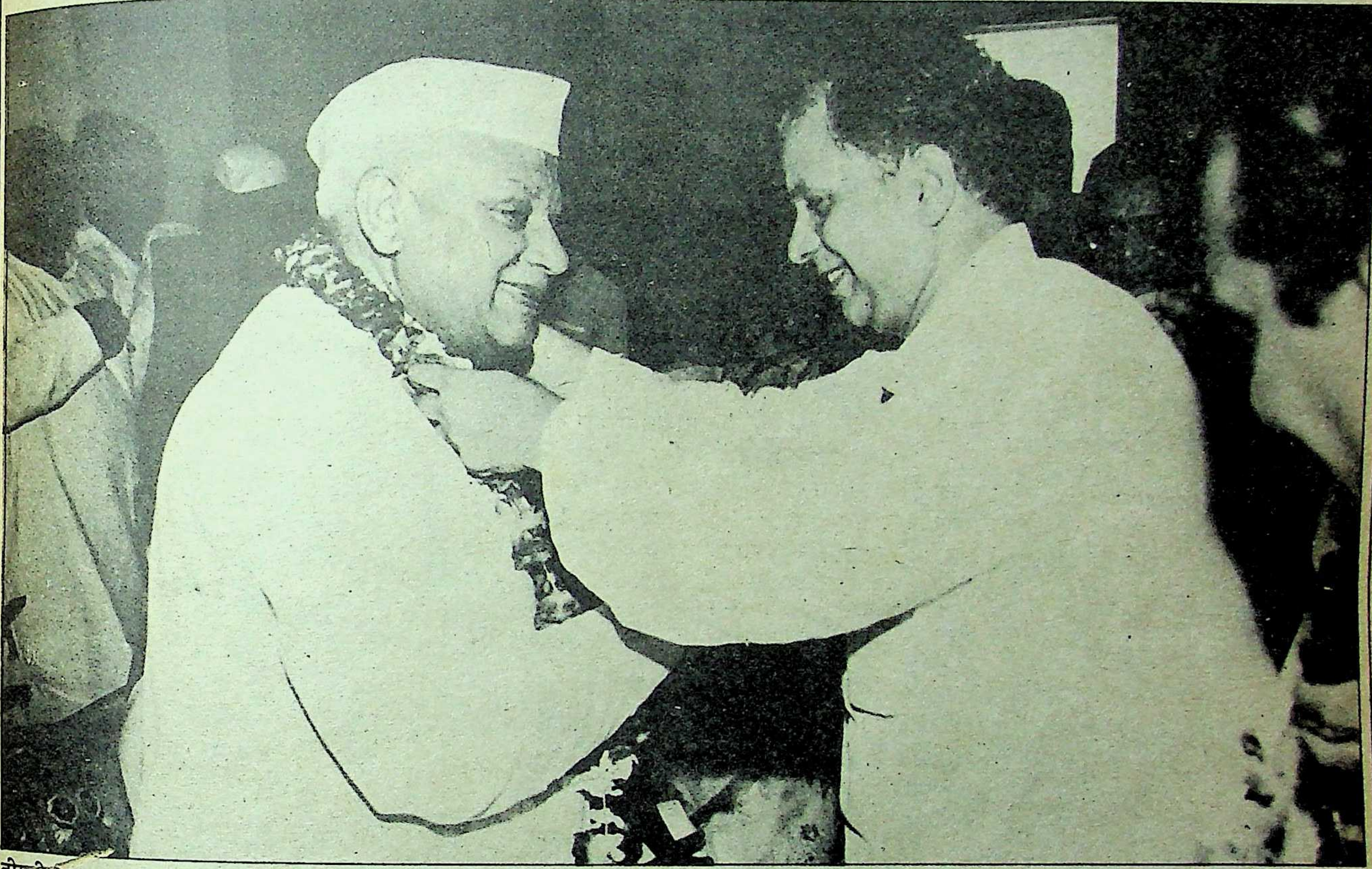

तीसरी बार : अम्मार रिजवी नारायण दत्त तिवारी को माला पहनाते हुए

केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजीव गांधी के बाद दूसरा स्थान नारायण दत्त तिवारी को मिला हुआ था। वह केंद्र में हिंदी क्षेत्र के वरिष्ठतम राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। लेकिन तिवारी को मुख्यमंत्री बनाये जाने के बाद ऐसा कोई नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं बचा। क्या तिवारी को सत्ता केंद्र से हटाकर उत्तर प्रदेश में सीमित करने के पीछे पार्टी की कोई आंतरिक चाल थी या वीपी सिंह के प्रकोप से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए उन्हें यहां भेजा गया है ?

वीर बहादुर को हटाया गया, इसका कारण इलाहाबाद हो सकता है, पर वीर बहादुर के समान स्तर पर नारायण दत्त तिवारी को क्यों खड़ा किया गया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तिवारीजी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या यह आपकी पदावनति है, तो वह पहले इसे टाल गये, पर बाद में उनका जवाब वही था, जिसे प्रायः सब कांग्रेसी नेता दोहराते हैं कि मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और कमांडर जिस मोर्चे पर भेजेगा, अनुशासनबद्ध सिपाही की तरह उस मोर्चे पर जाऊंगा।

जो विश्लेषक तिवारीजी के लखनऊ आने को उनकी पदावनति मानते हैं, उनका कहना है कि दिल्ली में तिवारीजी की स्थिति राजीव गांधी के बाद देश के सबसे बड़े नेता की थी। वह राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेता थे, पर तिवारीजी को इस स्थिति से हटाने के लिए दिल्ली दरबार में भारी जोड़-तोड़ चल रही थी। इसके लिए जो तत्व काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत पहले एक अंग्रेजी साप्ताहिक में यह 'जानकारी' छपवायी थी कि जब जैल सिंह को तैयार किया जा रहा था वह राजीव गांधी को बर्खास्त कर दें, तब राजीव गांधी के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिनके नाम लिये जा रहे थे, उनमें तिवारीजी का भी नाम भी था। यह 'जानकारी' कितनी सही और कितनी गलत थी, यह एक अलग बात है पर इससे इतना पता तो चलता ही है कि नारायण दत्त तिवारी ऐसे नेता हैं, जिनके बारे में सभी पक्ष सहमत हो सकते हैं। उनकी यह लोकप्रियता ही दुर्योधन के पैर में पद्म के चिह्न की तरह राजयोग का कारण बनने के बजाय उनकी पदावनति का कारण बनी हो, तो इसमें किसी को क्या आश्चर्य।

परदे के पीछे अरसे से जो उठा-पटक चल रही थी, उसका पूर्वार्द्ध तो सम्पन्न हो गया। जो लोग तिवारीजी को दिल्ली से और वीर बहादुर को लखनऊ से हटाना चाहते थे, वह सफल हो गये हैं, पर जिस उद्देश्य से यह तब्दीली हुई, क्या वह भी पूरा हो सकेगा ?

वर्ष १९८४-८५ के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि तिवारीजी के पास जादू की ऐसी कोई

साक्षात्कार/ नारायण दत्त तिवारी

मैं पार्टी का सिपाही हूं

अगस्त १९८४ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीपति मिश्र सरकार की लगातार गिर रही साख को बचाने के लिए जहां नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री पद का राज्याभिषेक कर लखनऊ भेजा था, वहीं ठीक ३५ दिनों बाद दिल्ली से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस उद्देश्य से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था कि वे प्रदेश में पार्टी की डगमगाती नैया को किनारे लगायेंगे। इन दोनों नेताओं के पद-भार ग्रहण करने के कोई तीन महीने बाद (अक्टूबर १९८४) में श्रीमती गांधी तो इस दुनिया से चली गयी थीं, लेकिन राजा-तिवारी की जोड़ी ने दिसम्बर १९८४ में हुए लोकसभा चुनाव में सहानुभूति लहर के सहारे ८५ में से ८३ सीटें राजीव गांधी की झोली में डाल दी थीं। इसी जोड़ी ने मार्च १९८५ में हुए विधानसभा चुनावों में भी ४२५ सीटों में से २६८ पर पार्टी उम्मीदवारों को जितवाकर विधानसभा में इंका को बहुमत दिला दिया था। उस समय तक श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति का असर काफी कम हो चुका था। लेकिन जिस राजा और तिवारी की जोड़ी ने १९८४ में संगठन और सरकार को संकट से उबारने का काम किया था, आज उसी में से एक (राजा) पार्टी के लिए संकट बन गये हैं और दूसरे (नारायण दत्त तिवारी), राजा से पार्टी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में जूझने के लिए भेज दिये गये हैं।

दरअसल, नारायणदत्त तिवारी होने का मतलब है, तुरुप का वह इक्का जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद इसी कारण श्रीमती गांधी संकट के समय में तुरुप के इस इक्के को दांव पर लगाती रही हैं। अब, जबकि राजीव गांधी को अपने ही गढ़ में राजा ने चुनौती दे दी है, तो उन्हें भी तुरुप के इसी इक्के का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा।

उत्तर प्रदेश में हाल में हुए तीनों उपचुनावों में इंका की जबरदस्त पराजय तथा मुस्लिम मतदाताओं के पूरी तरह मुंह मोड़ लेने से दिल्ली दरबार को इस बात का अहसास होने लगा है कि हरियाणा की तरह उनका अपना प्रदेश भी जो केंद्र में सरकार बनाने और मिटाने में निर्णायक भूमिका अदा करता है, हाथ से निकल रहा है। इसीलिए नारायण दत्त तिवारी को एक बार फिर प्रदेश की बागडोर सौंप दी गयी और तिवारी तीसरी बार मुख्यमंत्री होकर आ गये।

तिवारी उत्तर प्रदेश के सबसे कुशल प्रशासक माने जाने वाले मुख्यमंत्रियों में रहे हैं। पर उन्हें प्रदेश में ज्यादा कुछ करने का मौका कभी नहीं मिला। पहली बार २१ जनवरी, १९७६ को वह मुख्यमंत्री बने, तो देश में आपातकालीन स्थिति का असामान्य माहौल था। उस समय श्रीमती गांधी ने सजा के रूप में बहुगुणा को मुख्यमंत्री-पद से हटाया था। तिवारी उस समय केवल सवा साल ही मुख्यमंत्री-पद पर रह पाये, क्योंकि १९७७ के आम चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। दूसरी बार भी पिछले आम चुनाव के समय वह केवल १३ महीने ही अपने पद पर रह पाये और १३ महीनों में उनका कभी लखनऊ रहने में मन नहीं लगा। अब उन्हें फिर अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए यहां भेज दिया गया है।

नैनीताल जिले के बल्यूटी गांव में १८ अक्टूबर, १९२५ को पैदा हुए नारायणदत्त तिवारी सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और जेल गये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह अपने गांव वापस लौटे, तो उस समय तक उन्होंने लाल टोपी अपना ली थी। सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में तिवारी ने सक्रिय राजनीति शुरू की। पहली बार १९५२ में वह नैनीताल से राज्य विधानसभा के लिए चुने गये। १९५७ में वह फिर चुने गये। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गये। वह अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के संयोजक बनाये गये और १९६९ में पुनः काशीपुर (नैनीताल) से विधानसभा के लिए चुने गये। इस बार चन्द्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया। १९६९ के ऐतिहासिक कांग्रेस विभाजन के समय गुप्त-मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर इंदिरा गांधी में आस्था व्यक्त करने वाले वह पहले मंत्री थे।

वर्ष १९७० में वह कांग्रेस व भारतीय क्रान्तिदल की मिलीजुली सरकार में वित्त व संसदीय कार्य विभाग के मंत्री बने। इसी मंत्रिमंडल में पहली बार वीर बहादुर सिंह उपमंत्री बने थे। उसके बाद तिवारी लगातार विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री बने रहे। १९७७ में जबकि जनता तूफान में कांग्रेस के कई गढ़ ढह गये, तिवारी काशीपुर से फिर चुने गये और विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने। बहुत कम सदस्यों वाली कांग्रेस व विपक्ष के नेता के रूप में वह प्रभावशाली बनकर उभरे थे। जनवरी १९८० में वह नैनीताल से लोकसभा का चुनाव जीते और केन्द्र में कैबिनेट मंत्री बनाये गये। १९८४ के अन्त में वह फिर उत्तर प्रदेश वापस लौटे। २५ सितम्बर १९८५ को पुनः केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल किये गये।

दिल्ली दरबार का नारायण दत्त तिवारी को लखनऊ भेजने का मुख्य उद्देश्य अगले वर्ष के अंत में या पहले होने वाले आम चुनाव में इंका की डूबती नैया को किनारे लगाना है। यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा बहुत ही हंगामेदार है। जहां शोरगुल, नारेबाजी और हंगामे की कौन कहे, जूते-चप्पल भी चलते हैं, हाथापाई भी होती है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी तिवारीजी कभी विचलित नहीं हुए। कभी उनको क्रुद्ध होते नहीं देखा। वह एक कुशल और प्रभावशाली वक्ता हैं। वैसे तो राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, जिस पर समय-समय पर कोई-न-कोई आरोप न लगा हो, लेकिन तिवारी के विरुद्ध आज तक कोई गंभीर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है।

एक समय में विपक्षियों द्वारा 'संजय की सवारी' अथवा 'नयी दिल्ली तिवारी' का संबोधन सुनकर भी तिवारी बस मुस्कुराते रहते थे। अब इस समय तिवारी के सामने केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम यह है कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोधी जो हवा चल पड़ी है, उसको अपनी योग्यता, क्षमता तथा चतुराई के बल पर १८ महीनों के अंदर बदलकर इस प्रकार कांग्रेस के पक्ष में कर दें कि सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा बनी रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय नेताओं ने तिवारी को ही योग्यतम समझा है और इसीलिए तीसरी बार प्रदेश के नेतृत्व का भार उनके कंधों पर डाला गया है। मुख्यमंत्री का पद-भार ग्रहण करने के बाद 'माया' ने नारायण दत्त तिवारी से सामयिक मुद्दों पर बातें की हैं। प्रस्तुत हैं वार्ता के अंश:

माया: *आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में राजीव गांधी के बाद नम्बर दो पर थे, अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाये जाने पर आपको कैसा लग रहा है?*

नारायण दत्त तिवारी: यह इम्तहान और चुनौती भरा सम्मान का पद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोटा नहीं है। इस पद की किसी अन्य पद से कम मर्यादा नहीं है। इस पर आकर मैं अपने को धन्य मानता हूं। देश की सेवा में कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है।

माया: *पिछली बार (अगस्त १९८४ में) आपको*

दिल्ली से उत्तर प्रदेश इसलिए भेजा गया था, ताकि आप चुनाव में पार्टी को विजय दिला सकें। क्या इस बार भी यही उद्देश्य है?

तिवारी: अभी चुनाव की कोई बात नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूं। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक के रूप में भेजा गया हूं। जो भी काम सौंपा जायेगा, अनुशासित सिपाही की तरह करूंगा। प्रजातंत्र में चुनाव आते-जाते ही रहते हैं। मुझे यहां काम करने के लिए भेजा गया है।

माया: ***पिछली बार (सितम्बर १९८५ में) जब आपने मुख्यमंत्री-पद से इस्तीफा दिया था, तब यह कहा था कि यहां काम करने का माहौल नहीं है। पार्टी के लोग काम करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। क्या पिछले पौने तीन सालों में काम करने का माहौल बन गया है?***

तिवारी: उस समय की बात दूसरी थी। मैंने कहा था कि यहां काम का माहौल और बनाया जा सकता है। मैं पार्टी के सभी लोगों, विधायकों और विपक्षी दल के लोगों का पूरा सहयोग काम का माहौल बनाने में लूंगा। अपने पूर्वाधिकारी श्री वीरबहादुर जी से भी सलाह-मशविरा करता रहूंगा। उनके द्वारा शुरू किये गये विकास कार्यों को और गति दूंगा।

माया: ***वीर बहादुर सिंह ने कहा है कि वह प्रदेश को समस्यारहित छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में तो आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा।***

तिवारी: इतना बड़ा प्रदेश है। नयी-नयी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। जब काम होता है, तो समस्याएं भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं।

माया: ***आपके एक पुराने मित्र इलाहाबाद के उपचुनाव के बाद आपकी पार्टी के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। आखिर अपने मित्र राजा मांडा की चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे?***

तिवारी: देखिए, न तो मैं यहां किसी को चुनौती देने आया हूं और न किसी से लड़ाई लड़ने। मैं तो प्रदेश में काम करने आया हूं। मैं तो सभी के सहयोग से प्रदेश के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं।

हार और जीत दोनों से सबक लेना चाहिए। दरअसल जहां पर विपक्ष एक हो जाता है, वहां कांग्रेस को परेशानी होती है। उसकी (कांग्रेस की) जीत भी मुश्किल हो जाती है। हमें जनमत का आदर करना चाहिए। हार के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। जहां जो कमी हो, उसे दूर किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल इसलिए एक होता है कि कांग्रेस को हटाया जाये, तो यह ठीक नहीं है।

माया: ***हाल में हुए तीनों उपचुनावों में पार्टी की पराजय को आप किस रूप में देखते हैं?***

तिवारी: हार और जीत दोनों से सबक लेना चाहिए। दरअसल जहां पर विपक्ष एक हो जाता है, वहां कांग्रेस को परेशानी होती है। उसकी (कांग्रेस की) जीत भी मुश्किल हो जाती है। हमें जनमत का आदर करना चाहिए। हार के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। जहां जो कमी हो उसे दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष केवल इसलिए एक होता है कि कांग्रेस को हटाया जाये, तो यह ठीक नहीं है। इस सिद्धान्तहीन गठबंधन से देश का भला नहीं हो सकता। अगर किन्हीं कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर विपक्षी एकता हो, तब तो ठीक है। इस समय विपक्ष अपने भले की सोच रहा है, जबकि कांग्रेस जनता के भले के लिए सोचती है।

माया: ***आम चर्चा है कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच कर आपको उत्तर प्रदेश भिजवाया है, ताकि केन्द्र में बढ़ रहे आपके प्रभाव को कम किया जा सके।***

तिवारी: इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। जहां लगा दिया जाता हूं, निष्ठापूर्वक लग जाता हूं।

माया: ***आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानपरिषद का सदस्य बनेंगे?***

तिवारी: यह तो पार्टी हाई कमान ही तय करेगा।

माया: ***पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की तरह क्या आप भी हर चीज के लिए निर्देश प्राप्त करने बार-बार दिल्ली की दौड़ लगायेंगे?***

तिवारी: मैं कार्य के हिसाब से दिल्ली जाऊंगा। केन्द्र से तालमेल बिठाना जरूरी है। जब भी जरूरत होगी, मैं सुझाव लेने और सुझाव देने दिल्ली अवश्य जाऊंगा। विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए दिल्ली जाना कोई बुरा तो नहीं है।

माया: ***इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक के साथ ही प्रायः सभी वर्ग के लोग आंदोलित हैं। उन्हें आप कैसे शान्त करेंगे?***

तिवारी: कर्मचारी वर्ग से मेरा बहुत करीब का रिश्ता रहा है। मैं उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का पूरा प्रयास करूंगा। कर्मचारी और शिक्षक नेताओं से बात करूंगा। वेतन समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लूंगा।

माया: ***हाल के उपचुनावों से यह साबित हुआ है कि हरिजन और मुसलमान दोनों ही कांग्रेस से अलग हो गये हैं। इस 'वोट बैंक' को पार्टी से जोड़ने का काम आप कैसे करेंगे?***

तिवारी: हरिजन और मुसलमान दोनों ही समाज के अंग हैं। समाज के दूसरे वर्गों की तरह उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें कुछ शिकायतें भी होंगी। मैं सबसे बात करूंगा। उनकी समस्याएं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा।

—अजय कुमार

“वीरबहादुर की एक कमी यह बतायी गयी कि वह इलाहाबाद में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने में असफल रहे हैं। पर क्या तिवारीजी अगले चुनाव में यह करिश्मा दिखा सकते हैं?”

छड़ी नहीं, जिसके बल पर वह बेहोश पड़ी कांग्रेस को होश में ला सकें। चुनाव जीतने के लिए पार्टी की एक सक्रिय फौज चाहिए, जिसका कहीं पता नहीं है। पार्टी को जिलाने का एक प्रयास कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, पर जाली सदस्यता के बोझ के नीचे पार्टी ऐसी दबी कि अभी तक निकल नहीं सकी। पार्टी में नेताओं की भीड़ तो है, पर कार्यकर्ता का कहीं पता नहीं है। इलाहाबाद की हार ने इस सचाई को कदम-कदम पर उजागर किया है। यह आशा भी नहीं की जा सकती कि साल-छह माह में पार्टी का कोई ऐसा ढांचा खड़ा किया जा सकता है जो प्रभावी हो।

पार्टी अपनी इस कमजोरी को समझती है। उसने सफलता की सीधी पगडंडी यह पकड़ी है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाये। वीर बहादुर की एक कमी यह बतायी गयी कि वह इलाहाबाद में सरकारी तंत्र के इस्तेमाल में असफल रहे हैं। पर क्या तिवारीजी अगले चुनाव में यह करिश्मा दिखा सकते हैं? जो यह आशा लगाये बैठे हैं, वे दही के धोखे चूना खा रहे हैं। वर्ष १९७७ और फिर १९८० के चुनाव परिणाम से कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सबक सीखे थे। उनके सामने भूरे लाल और विनोद पाण्डे के भी उदाहरण हैं। फिर दिल्ली दरबार के 'कम्प्यूटर छोकरे'-जो नतीजे अपने कम्पयूटरों से निकालते हैं, वे गलत भी हो सकते हैं, पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो निष्कर्ष मैदान में खड़े होकर निकालते हैं, वे ९९ फीसदी तक सही उतरते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इलाहाबाद में मतदान से १५ दिन पूर्व 'माया' से कहा था, “सुनील शास्त्री एक लाख वोट से हारेंगे, मेरे आंकड़े में १० हजार वोट इधर-उधर जोड़कर चुनाव नतीजे पढ़ियेगा।” इस अधिकारी की बात सौ फीसदी सही निकली। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक लाख दस हजार मतों से जीते। प्रदेश के ये वरिष्ठ अधिकारी १९८९-९० की हवा का रुख अभी से पहचान रहे हैं। इलाहाबाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे तन कर सीधे खड़े होंगे। दरअसल यह भारत में लोकतंत्र की स्वस्थ शुरुआत का संकेत है। कांग्रेस यदि इस भ्रम में है कि अफसरों के सहारे वह चुनाव जीत लेगी, तो उसे अब अपना मन साफ कर लेना

चाहिए। अधिकारी अब किसी पार्टी की बंदूक दागने को अपना कंधा देने को राजी नहीं होगा।

नारायण दत्त तिवारी जो काम करने आये हैं, उसको अंजाम कैसे देंगे? तिवारीजी ईमानदार हैं। वह कहते हैं कि प्रतिपक्ष जब-जब इकट्ठा हुआ है, तब-तब कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा हुई हैं। उन्होंने अपना काम पूरा करने के लिए भेद नीति का सहारा लेने का भी संकेत दिया है। तिवारीजी प्रतिपक्ष के प्रत्येक नेता से मिलेंगे। वह सबसे कहेंगे कि कांग्रेस को हटाने के लिए एक होने के बजाय देश के विकास के लिए कांग्रेस के साथ मिल कर काम करने को राजी हों। कांग्रेस ने यह प्रयोग १९७९ में किया था और हेमवती नन्दन बहुगुणा जनता पार्टी से उड़ कर कांग्रेस की [illegible] जा बैठे थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए ताजा उपचुनावों में भाजपा और लोकदल लड़ मरे और इसका लाभ कांग्रेस को मिला। इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप की जीत से चन्द्रशेखर को जो पीड़ा हुई है, उसे वह छिपा नहीं सके।

सुबह छींक आयेगी, इस उम्मीद में प्रतिपक्ष के कई नेताओं ने शाम से ही अपने मुंह फैलाने शुरू कर दिये हैं। कांग्रेस के लिए यह अच्छा संकेत है और तिवारीजी इससे फायदा उठाने के तरीके भी जानते हैं, पर उनकी दिक्कत यह है कि उनके अपने घरवाले ही उनको चैन से बैठने और काम करने नहीं देंगे। मोर्चाबन्दी अभी से शुरू हो गयी है। विश्वनाथ प्रताप की जीत ने कांग्रेस पार्टी के भीतर पदलोलुपों को पूरी कीमत वसूल करने को उकसाया है। शिकायत की जा रही है कि जो इलाहाबाद की हार के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें फिर से मंत्रिपद दे दिया गया है। तिवारीजी घर के प्रत्येक असंतुष्ट को संतुष्ट नहीं कर सकते। पदों की इतनी रेवड़ियां भी उनके पास नहीं कि सबको प्रसाद देकर खुश कर सकें। फिर वे शक्तियां भी अब परदे के पीछे से काम करेंगी, जिन्होंने तिवारी को दिल्ली से लखनऊ खिसकाया है। तिवारीजी काम कर सकते हैं, पर उनकी हालत पंख कटे कबूतर या पेटी बंधी बुलबुल जैसी है जो चक्कस पर बैठी है।

—रामपाल सिंह

ऐसे चुने गये तिवारीजी नेता

२४ जून की सुबह ही यह बात साफ हो गयी थी कि वीर बहादुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिये जायेंगे और उनके स्थान पर नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी दिन शाम गुलामनबी आजाद के साथ एचकेएल भगत और बिंदेश्वरी दुबे, केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में दिल्ली से लखनऊ आ गये थे। तीनों ने वीर बहादुर सिंह से करीब आधे घंटे तक राजभवन में विचार विमर्श किया।

चूंकि नारायण दत्त तिवारी लंदन से वापस नहीं आ सके थे और अगली सुबह वीर बहादुर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेनी थी, इसलिए विधानमंडल दल की बैठक रात १० बजे बुला ली गयी। सब कुछ पहले से तय हो चुका था, इसलिए बैठक मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलायी गयी थी। इस बैठक में बमुश्किल ७०-८० विधायक ही पहुंच सके थे। लेकिन गुलामनबी आजाद ने १५१ विधायकों की उपस्थिति का दावा किया।

यह पहली बार हुआ था कि विधानमंडल दल जिसे नेता चुन रहा था, वह बैठक में उपस्थित होने की कौन कहे, उस समय तक अपने देश में ही मौजूद नहीं था। इसके पूर्व १९८० में संजय गांधी को भी उनकी अनुपस्थिति में इंका विधानमंडल दल ने नेता चुना था, पर संजय गांधी ने मुख्यमंत्री-पद की शपथ नहीं ली थी। अपनी अनुपस्थिति में नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले नारायण दत्त तिवारी पहले व्यक्ति हैं। यह भी एक विडंबना ही थी कि बैठक की समाप्ति पर न तो 'राजीव गांधी जिंदाबाद' के नारे लगे और न ही नेता चुने जाने की खुशी में किसी ने नारायण दत्त तिवारी के जिंदाबाद का नारा लगाया। इस पर इंका के एक तेज तर्रार विधायक ने कहा, "जब ऊपर से नेता थोपा जायेगा, तो ऐसा ही होगा।" एक अन्य विधायक की प्रतिक्रिया थी, "चूंकि तिवारीजी

मौजूद नहीं थे, इसलिए नारेबाजी नहीं हुई। कांग्रेस में तो अब मुंह देखी नारेबाजी ही होती है।" तिवारीजी की समर्थक एक महिला विधायक का कहना था, "अगर इस मौके पर हम तिवारीजी जिंदाबाद के नारे लगाते तो वीर बहादुर का मुंह बन जाता।"

शायद यही वजह थी कि २५ जून की सुबह सात बजे जब नारायण दत्त तिवारी का विमान अमौसी हवाई अड्डे पर उतरा, तो उनके स्वागत के लिए कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता वहां मौजूद नहीं था। डाक्टर अम्मार रिजवी उनके साथ दिल्ली से ही आये थे। हवाई अड्डे से तिवारीजी सीधे वीर बहादुर सिंह से मिलने कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास गये। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद उनकी वीर बहादुर सिंह से भेंट हुई। पांच मिनट तक दोनों नेताओं ने वार्ता की, फिर वीर बहादुर दिल्ली के लिए रवाना हो गये। लगभग साढ़े नौ बजे वह राजभवन के दरबार हाल में पहुंचे, जहां शपथ-ग्रहण समारोह आयोजित था। तिवारी के वहां पहुचते ही कांग्रेसियों में पैर छूने की होड़ लग गयी। एक विधायक ने तो चिल्लाकर यहां तक कह डाला "तिवारीजी अब आप आ गये हैं। अब उ०प्र० बच जायेगा।" तिवारीजी ने पीछे मुड़कर उस से हाथ मिलाया। शपथ के लिए बने मंच पर कुल ६ माइक लगे थे। अभी तक यह परंपरा रही है कि मंत्री-पद की शपथ लेने वालों के लिए अलग से कुरसियां लगी रहती थीं, जिन पर नाम की चिट लगायी जाती थी। इस बार शपथ लेने वाले लोग सामान्य व्यक्तियों के साथ दर्शकों के बीच बैठे। अंतिम समय तक किसी को यही पता नहीं चला कि कौन-कौन मंत्री बन रहे हैं। अजीत प्रताप सिंह को छोड़कर शेष ११ मंत्री वीर बहादुर के मंत्रिमंडल में भी थे।

मंत्रियों के विभागों में नारायण दत्त तिवारी ने मामूली फेरबदल की है। लोकपति त्रिपाठी जो पिछले आठ वर्षों से स्वास्थ्य विभाग पर काबिज थे, को सिंचाई विभाग सौंपा गया। गोपीनाथ दीक्षित से गृहमंत्रालय छीन कर उन्हें 'पदावनत' कर स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है। अरुण कुमार सिंह मुन्ना का कद भी काफी कम कर दिया गया। उनसे सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण विभाग छीन कर उन्हें पशुधन एवं दुग्ध विकास जैसा छोटा विभाग दिया गया है। डा० अम्मार रिजवी को संसदीय कार्य के साथ उनका पुराना एवं मनपसंद सार्वजनिक निर्माण विभाग सौंप कर उनका महत्व बढ़ाया गया। मजेदार बात तो यह है कि विपक्ष का सहयोग लेने की घोषणा करने वाले नारायण दत्त तिवारी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष का एक भी नेता मौजूद नहीं था।

—निशीथ जोशी

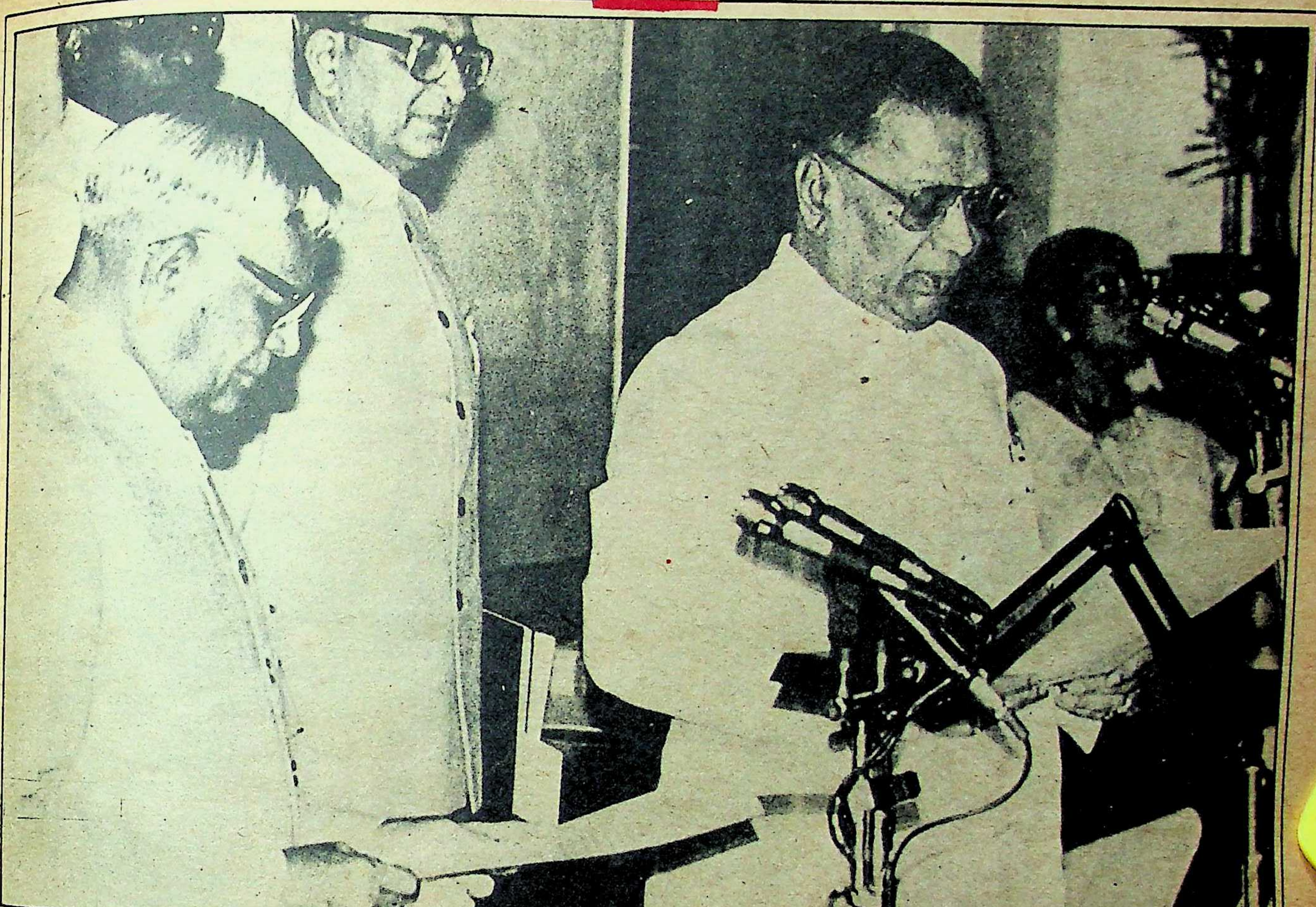

पवार और वसंत दादा का भय : शपथ ग्रहण करते वित्त मंत्री शंकरराव चह्वाण

केंद्रीय मंत्रिमंडल

आपातकालीन फेरबदल किस लिए ?

राजीव गांधी ने साढ़े तीन वर्ष में २५वीं बार अपने मंत्रिमंडल को फिर उलटा-पलटा है! ‘नये मंत्रियों को शामिल करने और विभागों में फेरबदल करने के पीछे क्या राजीव गांधी ने योग्यता को महत्व दिया है या पार्टी में असंतोष को दबाने के लिए परेशानी पैदा करने वाले लोगों को सत्ता बांट दी है। क्या यह नया बंदोबस्त राजीव गांधी और कांग्रेस-इ को उन खतरों से बचा सकेगा जो उपचुनावों की हार के बाद उनके सामने खड़े हो गये हैं?

“बदली तो बहुत हुई, लेकिन खुद नहीं बदले,” मंत्री बनने से वंचित एक पुराने केंद्रीय मंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी करने से अपने को तब रोक नहीं पाये, जब २५ जून को उनकी कार बारह बजे के लगभग राष्ट्रपति भवन के ऊंचे फाटक से शपथ ग्रहण के बाद निकल रही थी। यह टिप्पणी हाल में संपन्न इलाहाबाद के ऐतिहासिक उपचुनाव के बाद दरपेश कांग्रेस की मौजूदा और भावी कार्यनीति और रणनीति पर पूर्णतया खरी उतरती है। राजीव गांधी अभी बदले नहीं। न ही उनके सलाहकार, जिनमें कुछ मुंहलगे नौकरशाह और नौसिखिये राजनीतिक शामिल हैं।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि भावी आमचुनावों में हिंदीभाषी क्षेत्र में पार्टी की स्थिति क्या होगी? दरअसल २३ जून की शाम और २४ जून की रात के बीच भी कम-से-कम पांच वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के भविष्य को तोड़-मरोड़कर कुछ लोगों को बेहद नाराज कर दिया गया है।

लोकपति के साथ मज़ाक : उसी दिन करीब ८ बजे रात को जबकि नारायण दत्त तिवारी एयर इंडिया के विमान से लंदन के हवाई अड्डे हीथ्रो पर

उतरे ही होंगे कि लोकपति त्रिपाठी को खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वयं उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बधाई दे रहे थे। त्रिपाठी ने अनुमति मांगी उसी वक्त लखनऊ वापस जाने की, तो उनसे यह कहा गया कि वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की अनौपचारिक सूची तैयार करें और सुबह हवाई अड्डे जाने के पहले प्रधानमंत्री सचिवालय को सौंप दें। लगभग इसी के कुछ घंटे पूर्व राजीव गांधी के एक करीबी सलाहकार यह सांत्वना दे रहे थे कि वीरबहादुर सिंह को इतनी जल्दी हटाया नहीं जायेगा। मध्य रात्रि के लगभग नारायण दत्त तिवारी को टेलीफोन से लंदन में सूचित किया गया कि वह फौरन वापस आ जायें, क्योंकि उन्हें लखनऊ जाना है। दूसरे सलाहकार शंकरराव चह्वाण को बंबई फोन करके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुला चुके थे। उनसे कहा गया कि उनकी दिल्ली में जरूरत है। यह पूछने पर कि उनका उत्तराधिकारी किसे बनाने की सोच रहे हैं, राजीव गांधी ने न कोई जवाब दिया न ही सलाह ली।

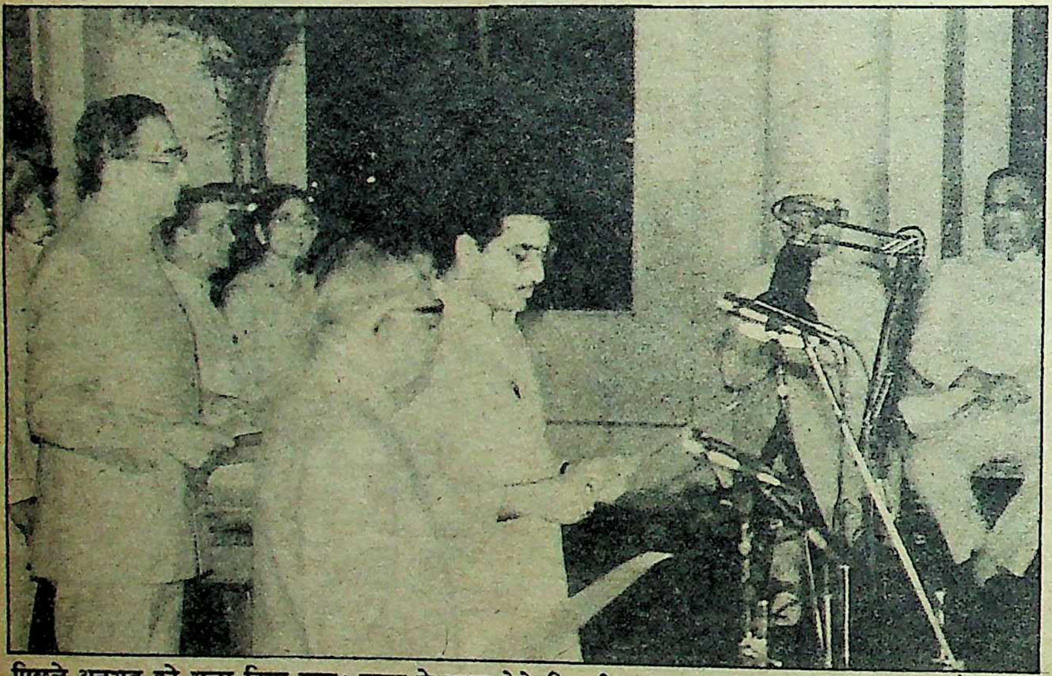

पिछले अनुभव को भुला दिया गया: शपथ के समय केके तिवारी

अगले दौरे में जब 'नामजद' मुख्यमंत्री लोकपति त्रिपाठी सुबह प्रधानमंत्री निवास पहुंचे, तो उनको यह संदेशा दिया गया कि अभी मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें लोग बहुत परेशान करेंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति फिलहाल टाल दी गयी है। कांग्रेस खेमे में अब यह कहा जा रहा है कि यह सुनकर त्रिपाठी तिलमिला उठे और रोषपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, "आप लोगों ने हमारे साथ तो भयंकर मजाक किया ही है। अगले साल आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा।"

सशंकित तिवारी: शाप कहिये या रोष, इस तरह की भावनाएं कई कांग्रेसी नेताओं के मन में आज विराजमान हैं। लंदन जाने के पहले, कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी और राजीव गांधी तथा उनके सलाहकारों में काफी लंबी बातचीत हुई थी और यह तय हो गया था कि लोकपति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाये जायेंगे और तिवारी को दिल्ली में ही बनाये रखा जायेगा और वाणिज्य मंत्रालय उनसे लेकर किसी और को दे दिया जायेगा। मगर कहा जाता है कि त्रिपाठी को आस बंधाने के बाद शाम को कुछ सलाहकारों की राय यह हुई कि एक पंथ दो काज का सहारा लिया जाये। ये लोग बहुत दिनों से प्रधानमंत्री को यह समझा-बुझा रहे थे कि तिवारी के इरादे कुछ विश्वनाथ प्रताप सिंह के ढर्रे पर बन-संवर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने खबर फैलायी थी कि तिवारी और वीपी सिंह में गुपचुप बैठक हुई है और बंबई के एक जानेमाने उद्योगपति के सहारे लिखित आरोप तिवारी पर लगवाये गये थे, किंतु तिवारी को कहां भेजा जाये इसकी समस्या थी, क्योंकि इन्हीं सलाहकारों के अनुसार वीरबहादुर सिंह उस समय वीपी सिंह का मुकाबला उत्तर प्रदेश में बड़ी कुशलता के साथ कर रहे थे। इन सलाहकारों को वह मौका अब सामने मौजूद दिखाई पड़ा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संभालना है तो तिवारी को वहां भेजा जाये, यह कहकर राजीव गांधी को लोकपति त्रिपाठी को दिया अपना वचन वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया। नतीजतन एक बहुत रुष्ट त्रिपाठी को लखनऊ भेजा गया और एक बहुत सशंकित तिवारी को दिल्ली से हटाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया।

मजे की बात यह है कि तिवारी के २७ जून के शपथग्रहण के पहले ही दिल्ली में यह खबर फैल गयी थी कि प्रधानमंत्री राजीव के करीबी हलके में यह खुशी जाहिर की जा रही है कि तिवारी का कद छोटा कर दिया गया है और दो-चार महीने बाद हौले से लखनऊ से भी उन्हें खिसका दिया जायेगा, यह कहकर कि कांग्रेस की छवि संभल नहीं पा रही है और पार्टी को उनके जैसे वरिष्ठ और संजीदा नेता की केंद्र में बेहद जरूरत है। कुछ लोग अर्जुन सिंह के साथ जो किया गया है उसकी मिसाल दे रहे हैं। आमचुनावों के पूर्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस-इ की छवि सुधारने का तर्क देकर सिंह को भोपाल भेजा गया और उनके पीछे फौरन ही मोतीलाल वोरा और माधवराज सिंधिया को लगा दिया गया, जिससे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम जनता को यह संकेत मिल जाये कि दिल्ली के दरबार में सिंह का मान-सम्मान घट गया है और जब खरसिया का उपचुनाव हुआ, तो वोरा के भाई के ही अखबार अमृत संदेश में अर्जुन सिंह के खिलाफ भरपूर प्रचार किया गया, जिससे वह (अर्जुन सिंह) हार जायें। भाजपा कार्यकर्ता उक्त समाचारपत्र की प्रतियां डटकर बांट रहे थे। दिल्ली में इस बात का दुख है कि अर्जुन सिंह बच गये, इस बात का नहीं कि उनका जैसा मुख्यमंत्री मात्र ८ हजार के लगभग वोट से जीता है। इसी बात को मुद्दा बनाकर हाल ही का फेरबदल किया गया। फेरबदल के दो दिन बाद प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने एक सुहानी शाम को कहा कि अर्जुन सिंह तो ठिकाने पर लग गये अब नारायण दत्त का भी इंतजाम हो जायेगा। तिवारी का लखनऊ में यह कहना कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत फख्र की बात है और इसको वह पदावनति नहीं समझते हैं, सिद्धांत रूप से तो ठीक है, परंतु उनकी तरह एक पारंपरिक और सुलझे हुए कांग्रेसी के विचार आज राजीव गांधी के आधुनिक व राजनीतिक सलाहकारों के विचारों से मेल नहीं खाते।

पर कतरने की राजनीति: कहने को तो हिंदी-भाषी क्षेत्र के दो मुख्य राज्यों मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश (जो लोकसभा में १३७ अर्थात एक लगभग चौथाई सदस्य भेजते हैं) में नये मुख्यमंत्री इसलिए लाये गये कि अगले आमचुनावों के लिए वे कांग्रेस को मजबूत कर सकें। मगर जिस संदेह के माहौल में मुख्यमंत्रियों को लाया गया है, उससे नहीं लगता कि इनको इतनी भी आजादी दी जायेगी कि वे पार्टी को मजबूत कर सकें। तिवारी की नियुक्ति के समय ऐसा नहीं लगता था। पर दिल्ली में आलम है कि प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने खुलेआम कहा कि तिवारी की नियुक्ति उनके पंख कतरने के लिए की गयी है, चूंकि वह भी प्रधानमंत्री की गद्दी के ख्वाब देखने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि एक गुप्तचर रपट के अनुसार ४० कांग्रेसी विधायक बहुत शीघ्र वीपी सिंह की तरफ जानेवाले हैं। २२ विधायक पहले ही से सिंह के साथ हैं। कहा जाता है कि अब वीरबहादुर सिंह और कुछ और मंत्रियों के जरिये इसकी रोकथाम की जायेगी। मगर यदि थोड़ें विधायक भी निकल गये तो वही तिवारी के लिए फंदा साबित होगा। "इन हालात में कैसे सुधार होगा?" फेरबदल से रुष्ट एक पुराने मंत्री ने 'माया' से अनौपचारिक रूप से कहा।

फेरबदल के पीछे राजीव गांधी के तीन मकसद जाहिर होते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों के एक प्रश्न कि क्या वह घबड़ा गये हैं के उत्तर में पूछा था कि 'क्या मैं घबराया हुआ लगता हूं।' "मगर असलियत यह है कि घबराहट ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री भयभीत भी हैं, अपने लिए, पार्टी

के लिए नहीं,'' यह टिप्पणी एक सासंद ने उस समय की जब 'माया' ने उनसे पूछा कि तिवारी और पवार की नियुक्ति के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। इन्हीं सांसद के साथ बैठे चाय पीते प्रधानमंत्री के एक भूतपूर्व करीबी सलाहकार ने कांग्रेस के भविष्य का बहुत गंभीर चित्र खींचा। उनके अनुसार, ''तिवारी और अर्जुन सिंह दोनों को नियंत्रण में रखा जायेगा। यहां तक कि दोनों प्रदेशों में गांधी के विश्वसनीय व्यक्ति मुख्यमंत्रियों पर निगाह रखेंगे। योजना है कि शक के दायरे में आ चुके तिवारी और अर्जुन सिंह जैसे राजनीतिक धुरंधरों को आमचुनावों से काफी समय पूर्व ही सत्ताविहीन और शक्तिहीन कर दिया जायेगा, क्योंकि यदि कांग्रेस को आमचुनावों में ३०० या कम सीटें मिलती हैं, तो अपने २०-३० संसद-सदस्यों के साथ ये राजनीतिक धुरंधर सौदेबाजी पर न उतर आयें।'' महज अगर छवि ठीक करने की बात होती, तो गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी को भी साथ-साथ हटा दिया जाता और अर्जुन सिंह को भोपाल भेजने के बाद उनके खिलाफ मुहिम का दिल्ली से आयोजन न किया जाता। जो मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में बना, वह ९९ प्रतिशत वही है जो वीरबहादुर सिंह का था। क्या इसका अर्थ यह है कि केवल वीरबहादुर सिंह खराब थे और तीनों सीटें उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से कांग्रेस के हाथ से निकलीं। अगर ऐसा था, तो वीरबहादुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों लिया गया ? एक कांग्रेसी सांसद ने इसका उत्तर देते हुए कहा, ''बात दरअसल यह है कि हर चाल महज इस मंतव्य से ही चली गयी है कि राजीवजी का नियंत्रण और सुरक्षा किस प्रकार कायम रहे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि सरकार और कांग्रेस की छवि का क्या होगा।''

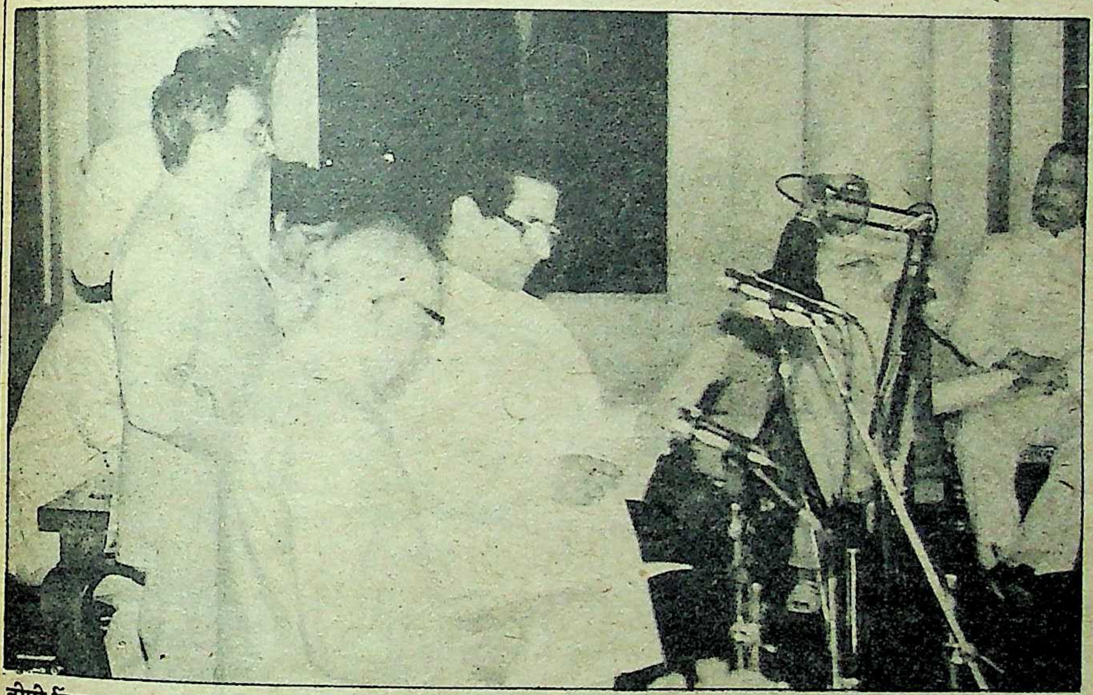

वीपी सिंह का गला फाड़कर विरोध करने के लिए : कल्पनाथ राय मंत्री-पद की शपथ लेते हुए

लालकृष्ण आडवाणी ने मौका न चूकते हुए 'माया' से कहा, ''केंद्रीय मंत्रिमंडल असफल मुख्यमंत्रियों की एक कूड़ेदानी बन गया है। इस समय आठ भूतपूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में हैं। इससे जाहिर होता है कि अभी भी जब आमचुनाव कुल डेढ़ साल दूर हैं, प्रशासन को दुरुस्त करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। हो वही रहा है जो चार साल से हो रहा है कि जब भी थोड़ी-सी दिक्कत आती है और राजीव विवादों के घेरे में फंसते हैं, तो उस समय ड्रामे के साथ थोड़ी सी फेरबदल यह दिखाने के लिए कर दी जाती है कि राजीव गांधी सब ठीक करने में जुट गये हैं। इसका नतीजा यह है कि औसतन उन्होंने हर दूसरे महीने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया।

राजीव की मजबूरियां : वाणिज्य और कपड़ा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर सिंह, पी चिदंबरम, खुर्शीद आलम खान, ब्रह्मदत्त, रामनिवास मिर्धा, पीआर दासमुंशी, कृष्ण कुमार, नारायण दत्त तिवारी और अब दिनेश सिंह, आये और गये। विदेश मंत्रालय में नरसिम्हाराव की दो बार उठक-बैठक करायी जा चुकी है और ऐसा ही सलूक रक्षा मंत्रालय के साथ भी हुआ है। जाहिर है कि किस मंत्रालय के लिए कौन-सा मंत्री नियुक्त किया जायेगा, यह उसकी काबिलियत पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उसके ऊपर राजीव गांधी के सलाहकारों का कितना विश्वास है या किससे विद्रोह का खतरा अधिक है। २५ जून के फेरबदल में यह मजबूरियां जाहिर हो गयीं।

कोई दो महीने पूर्व बेनारस हवाई अड्डे पर कल्पनाथ राय राजीव गांधी के एक पुराने मित्र को अपने दिल की निराशा बताते-बताते गाली पर उतर आये थे। उनकी शिकायत यह थी कि जीजान से वीपी सिंह का विरोध करने के पश्चात् उनका कोई खयाल नहीं किया जा रहा है। शरद पवार को जब तीन माह पहले यह बताया गया था कि उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने भी अपना रुख बदल दिया था। दिल्ली में घबराहट इस [illegible] की थी कि [illegible] जो बहुत कटु शब्दों में राजीव गांधी के बारे में बातें कर रहे थे, पवार के साथ मिलकर बंबई में कोई बवंडर न शुरू कर दें। पवार को इसलिए यह जानते हुए भी कि वह एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नियंत्रण में नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब यह खबर है कि पवार ने कहा कि कि वह दिल्ली रोज-रोज दौड़ कर नहीं जायेंगे। उनके मंत्रिमंडल में एक व्यास को छोड़कर कोई भी राजीव गांधी का विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। रामाराव आदिक अभी भी अपनी 'मानहानि' भूले नहीं हैं। कहा जाता है कि कल्पनाथ राय और पवार की नियुक्ति इनके विरोध से भयभीत होकर की गयी। यह अवश्य है कि पवार एक कुशल प्रशासक हैं, मगर इनके साथ वीरबहादुर आदि मुख्यमंत्रियों की तरह निम्न व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। इसी कारण एसबी चाह्वाण को वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम ओहदा दिया गया है। इससे दिल्लीवाले यह आशा करते हैं कि बंबई के बड़े उद्योगपतियों, जो सभी पवार के समर्थकों में हैं, को पवार से अलग किया जा सकेगा। घूम-फिरकर बात वहीं आती है कि राजीव के सशंकित सलाहकारों ने दिल्ली से उन लोगों को हटा दिया, जिनसे वह खतरा महसूस करते थे और जिन लोगों से विद्रोह की शंका थी, उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें पद दे दिये। इस दावपेंच में यह खयाल नहीं रखा गया कि सरकार कैसे चलेगी और राजीव गांधी की अपनी छवि (जो इलाहाबाद उपचुनाव में निचले स्तर पर जाहिर हुई) को उभारने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। मोहरेबाजी अभी कायम है। अमरीका के जानेमाने साप्ताहिक 'टाइम' और 'न्यूजवीक' ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीत को 'मिस्टर क्लीन की जीत' कहा। १९८४ में मिस्टर क्लीन का खिताब राजीव गांधी का था। लंदन के मशहूर दैनिक 'द गार्डियन' ने कहा, ''राजीव ने घबराहट (पैनिक) का बटन दबाया : मंत्रिमंडल में फेरबदल।''

सलाहकारों का जाल : कहा जाता है कि उपचुनावों के नतीजों और अंग्रेजी दैनिक 'हिंदू' में बोफोर्स-दस्तावेज के छपने के बाद राजीव गांधी ने कड़े कदम उठाने का इरादा किया था, परंतु वह फिर अपने अदूरदर्शी सलाहकारों के शिकंजे से निकल नहीं पाये। इन सलाहकारों ने यह मान लिया है कि कांग्रेस-इ को अगले चुनाव में ३०० सीटें ही मिल पायेंगी। इसी आधार पर उन्होंने उन सबको दिल्ली से दूर और सत्ताविहीन करने की ठान ली है, जिनकी राजीव-निष्ठा संदेहास्पद मानी गयी। साथ में असंतुष्टों को अपने साथ रखने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। राजनीतिक विवाद का रूप ले चुके बोफोर्स जैसे मामलों को प्रशासनिक स्तर पर निपटाने का प्रयत्न शुरू किया गया है। इस रणनीति से पारंपरिक कांग्रेसी बहुत उदासी के साथ-साथ भयभीत हो रहा है कि या तो राजीवजी हार मानकर हताश हो गये हैं या अभी भी वह गलतफहमी में जनमानस के विचारों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी को अभी-भी आशा है कि मैनेजरी और

नौकरशाही की मदद से सभी विवादग्रस्त मसले हल कर वह आमचुनाव जीत लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल उनके इसी विश्वास की पुष्टि करता है।

बहुत उत्साह से विदेश मंत्रालय का कार्य कर रहे नटवर सिंह के साथ कमल कांत तिवारी को जोड़ देने से नटवर सिंह भी काफी निराश हुए हैं। केके तिवारी पब्लिक एंटरप्राइजिज मंत्रालय में अच्छा काम कर चुके थे, लेकिन उनके इस अनुभव को भुला दिया गया। कल्पनाथ राय को 'पावर' मंत्रालय दिया गया, जबकि वह उद्योग मंत्रालय में कुछ नहीं कर पाये थे। इस दृष्टिकोण से असल में मंत्रिमंडल बनाया ही नहीं गया कि कौन-सा मंत्रालय कौन ठीक तरह चला सकता है?

इससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री सचिवालय के ही हाथ में सरकार की बागडोर रहेगी। नरसिम्हा राव, केसी पंत, एसबी चह्वाण, बूटा सिंह, दिनेश सिंह जोकि महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सर्वेसर्वा हैं, का अपना राजनीतिक महत्व इतना कम है कि न तो ये गांधी के मुकाबले में आने की कभी सोचेंगे, न ही राजीव के चहेते सलाहकारों का विरोध करेंगे। इस प्रकार २५ जून के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उन लोगों को सौंप दिया गया है जो कि पार्टी के लिए काम पूरा करेंगे, मगर केंद्र की निगाह के नीचे। महाराष्ट्र मजबूरन एक 'खतरनाक' आदमी को दिया गया है, पर शिवराज पाटिल और एसबी चह्वाण को महत्वपूर्ण बनाया गया।

पंत उत्तर प्रदेश के होते हुए भी दिल्ली के सांसद हैं और केंद्र को मालूम है कि तिवारी पंत को अब गढ़वाल से उठने नहीं देंगे। राव का कोई ठिकाना नहीं है, न ही बूटा सिंह का। चह्वाण को बिना गांधी की मदद से पवार और दादा सांस नहीं लेने देंगे और दिनेश सिंह वीपी की लहर की वजह से कांग्रेस के सहारे के बिना कुछ नहीं कर पायेंगे।

सिर्फ राजीव की चिंता : आज की तारीख में इस तरह राजीव गांधी के सलाहकारों ने राजीव को एकमात्र कांग्रेस का सर्वेसर्वा बना दिया है और पूरे मंत्रिमंडल का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में सौंप दिया है। मगर उनकी छवि और कांग्रेस के बारे में जनता की धुंधली तस्वीर को किस प्रकार ठीक किया जाये, इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। वीपी सिंह का तो कहना है, "राजीव गांधी का पूरा दायरा ४०० सांसदों में ही सीमित होकर रह गया है। भारत और कांग्रेस ताक पर रख दी गयी है।"

बोफोर्स का मामला हर दफा की तरह कालीन के नीचे कर दिया गया है। सीबीआई को जांच के लिए 'हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेज सौंप दिये गये हैं। इससे ग्रामीण मतदाता जिसको कि यह बात मालूम हो गयी कि रक्षा सौदों में धांधली हुई है और पैसा खाया गया है, की शंका को दूर नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि यह दस्तावेज हिंदू को स्वीडिश प्रासीक्यूटर लार्स विंसबर्ग खुद दे रहे हैं। अगर ऐसा है, तो बोफोर्स का विवाद राजनीतिक तरीके से ही मतदाताओं के बीच सब बातों का खुलासा करके दूर किया जा सकता है, मगर इस वक्त एक भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस में ऐसा नहीं है जो जनता में जाकर गांधी और कांग्रेस को बचा सके। नारायण दत्त तिवारी और नरसिम्हा राव जैसे कुछ लोग हैं, पर इन्होंने अभी तक वीपी सिंह के खिलाफ मुंह नहीं खोला है। उलटा कांग्रेस में कल्पनाथ राय और केके तिवारी के स्तर के लोग ही वीपी सिंह की निंदा कर रहे हैं। पर इसका आम जनता पर उलटा असर होता है। कांग्रेस के भीतर से कोई नेता उठकर राजीव की गद्दी को खतरे में न डाल दे, इस बात से राजीव के सलाहकार इतने चिंतित हैं कि उन्हें फिक्र ही नहीं है, उस जनमत की जो वीपी सिंह के समर्थन में उभर रहा है। "उन्हें वीपी लहर को रोकने का या तो समय नहीं है, या चिंता नहीं है। इस बात की कोई रणनीति नहीं है कि वीपी सिंह को जनता से कैसे अलग किया जाये। सलाहकार सिर्फ राजीव को कांग्रेस के अंदरूनी खतरे से बचाने में लगे हैं।" यह टिप्पणी है उन दो सांसदों की जिन्होंने करीब सात दिन इलाहाबाद क्षेत्र में उपचुनाव के वक्त गुजारे थे। उनका कहना है, "आप देखना अमेठी में भी परेशानी शुरू हो जायेगी।" कहा जाता है कि विपक्ष की तैयारी है कि तिवारी और उनके मंत्रियों को अमेठी क्षेत्र में फंसाकर रखा जाये जिससे वे अन्यत्र ध्यान न दे सकें। एक गुप्तचर रपट के अनुसार कहा जाता है कि अमेठी में असंतोष पनपना शुरू हो गया है, क्योंकि साल भर से बोफोर्स के चक्कर में किसी ने अमेठी पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वीपी सिंह भी अमेठी में अभियान छेड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस में कोई वरिष्ठ नेता नहीं है जो वीपी सिंह का जनता के बीच आकर विरोध कर सके। जो हैं, उन्हें राजीव के सलाहकार उठने नहीं दे रहे हैं। अब सिर्फ एक रास्ता है कि राजीव खुद वीपी सिंह के खिलाफ मैदान में आयें। पर राजीव की अपनी छवि जनता के बीच गिर रही है।

> **कांग्रेस के भीतर से कोई नेता उठकर राजीव की गद्दी को खतरे में न डाल दे, इस बात से राजीव के सलाहकार इतने चिंतित हैं कि उन्हें फिक्र ही नहीं है उस जनमत की जो वीपी सिंह के समर्थन में उभर रहा है।**

उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की हार को नारायण दत्त तिवारी के पर कतरने का साधन बनाया गया। कहा गया कि इलाहाबाद में ब्राह्मणों का वोट तिवारीजी नहीं ले पाये। मगर गुलाम नबी आजाद जैसे लोग यथावत हैं। सतीश शर्मा वहीं जमे हैं। इन्हीं लोगों ने दूरदर्शन के 'रामायण' सीरियल में राम का अभिनय करनेवाले 'अरुण गोविल' को इलाहाबाद में प्रयोग करने की योजना बनायी थी। इसका बुरा असर देश ही नहीं विदेशों में भी हुआ है। लंदन की फ्लीट स्ट्रीट में चर्चा है कि किस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने चुनावों में धार्मिक विश्वास का दुरुपयोग किया और यह चर्चा इस वजह से भी जोर पकड़ गयी है, क्योंकि बीबीसी अपने चौथे चैनल पर 'रामायण' का प्रसारण शुरू करने जा रहा है। लंदन में अंग्रेजों ने अरुण गोविल के चित्र दिखाकर भारतीयों से पूछा कि क्या यह वही राम हैं, जिनका इलाहाबाद में दुरुपयोग किया गया।

स्पष्टतः राजीव पूरी तरह अपने अदूरदर्शी सलाहकारों के बीच फंसे हैं और सलाहकार बाहर की उभरती कड़वी सचाई को देखने में असमर्थ हैं। एक कांग्रेसी सांसद ने बड़ी वेदना के साथ 'माया' से कहा, "जब तक साउथ ब्लाक और ७, रेसकोर्स रोड के छोटे कमरों से माखनलाल फोतेदार, गोपी अरोड़ा और सतीश शर्मा जैसे लोगों की राय से ही १०३ वर्ष पुरानी पार्टी चलायी जायेगी, तो एक सौ चौथे साल में क्या गुजरेगा, ईश्वर और जनता जाने।" राजीव के एक भूतपूर्व सलाहकार कांग्रेसी ने 'माया' से कहा, "या तो राजीव बुरी तरह भयभीत हैं या बिलकुल निश्चिंत हैं और दोनों दशाएं खतरनाक हैं।"

लखनऊ से आये एक भूतपूर्व सांसद (जो हाल ही राजीव गांधी से मिलने के प्रयत्न में कई दिन दिल्ली में रहे) ने कहा, "पहले वीरबहादुर से गलत तरीके से वीपी सिंह का विरोध कराया गया। फिर इलाहाबाद में केंद्र की बदनामी की वजह से हार को लेकर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया। जो लोग अराजनीतिक तरीकों से राजीव के ऊपर होनेवाले प्रहारों का मुकाबला करते रहे, उन्हें ईनाम दिया गया और मंत्री बना दिया गया, भले ही उनके कारण राजीव की छवि और खराब क्यों न हुई हो।" इस भूतपूर्व सांसद के अनुसार, "कल्पनाथ राय इसलिए मंत्री बनाये गये हैं, जिससे वह विपक्ष की पहली कतार में बैठे वीपी सिंह का गला फाड़कर विरोध कर सकें और जो गंभीर और सही राजनीतिक परामर्श दे सकते थे, उन पर शक कर उन्हें दिल्ली से दूर फेंक दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 'मिस्टर क्लीन' का मेडल जनता से राजीव से निकलवाकर वीपी सिंह को पहनवा दिया है। ये लोग अभी भी कांग्रेस और भारत पर शासन कर रहे हैं।" इस भूतपूर्व संसद ने लंबी सांस लेते हुए कहा, "ये लोग राजीव को राजनीतिज्ञ नहीं बनने देंगे। यह भारत और हमारे दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।" मगर पुरानी कहावत है कि तूती की आवाज मयखाने में सुनायी नहीं देती और सत्ता का नशा कुछ देखने-समझने नहीं देता।

—विजय दत्त

अर्जुन सिंह

प्रेस पर कोपदृष्टि

प्रेस से लंबे अंतराल तक अपने मधुर व सौहार्द्रपूर्ण संबंधों के लिए विख्यात अर्जुन सिंह की नजर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर, लगता है, अखबारों के प्रति बदली हुई है। कुल लगभग डेढ़ लाख की प्रसार संख्या के दैनिक 'भास्कर' के स्वामित्व का मामला अभी भी अदालतों में अटका हुआ है और राज्य सरकार की गुपचुप, लेकिन घनी रुचि उसमें बरकरार है। 'भास्कर' का ग्वालियर संस्करण आज भी १२० किमी दूर झांसी में छप रहा है और रायपुर संस्करण का प्रकाशन शुरू नहीं हो सका है। 'भास्कर', रायपुर के रेजिडेंट संपादक रमेश नैयर के अनुसार, "अखबार को एक अप्रैल से प्रकाशित करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी और हमने ट्रायल भी ले लिया था, लेकिन मामले के न्यायालय की परिधि में चले जाने से प्रकाशन शुरू नहीं हो सका।"

'भास्कर' का रायपुर संस्करण कब शुरू होगा? कहा नहीं जा सकता। संपादकीय विभाग के करीब बीस व्यक्तियों के अलावा कुल करीब पचास लोगों के अमले को पिछले तीन माह से नियमित वेतन बांटा जा रहा है, जबकि छोटे-मोटे और नियमित कामों को छोड़ दें, तो वे हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं। मालिकों को डर है कि कहीं भरती किये गये लोग ऊबकर अन्यत्र न चल दें। तय है कि इस डर और फिजूल के खर्च ने उन्हें परेशानी में डाल रखा है।

अमृत संदेश : 'भास्कर' पर सरकार की वक्र दृष्टि फिरी नहीं है और इस बीच मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के लोगों ने एक और दैनिक पत्र से पगा मोल ले लिया है। यह अखबार है—रायपुर से प्रकाशित दैनिक 'अमृत संदेश' और इसके संपादक-प्रकाशक हैं—गोविंदलाल वोरा। वोरा के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री मोतीलाल वोरा के सगे छोटे भाई हैं, जिनसे इन दिनों अर्जुन सिंह व उनकी राजनीतिक बिरादरी की खासी ठनी है। वैसे तो 'अमृत संदेश' और अर्जुन गुट में काफी समय से ठनी हुई है, लेकिन खुल्लमखुल्ला तकरार और लांछन लगाने का मौका पिछले दिनों खरसिया उपचुनाव के दरम्यान आया।

मध्यप्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी के महामंत्री और अर्जुन सिंह के चहेते नेता ललित श्रीवास्तव ने ८ जून, १९८८ को खरसिया उपचुनाव के लिए इंका आलाकमान द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक सांसद रामसेवक चौधरी से लिखित शिकायत की—कि मोतीलाल वोरा के पुत्र अरविन्द वोरा और अनुज गोविंदलाल वोरा द्वारा प्रकाशित 'अमृत संदेश' व्यक्तिगत राजनीतिक राग-द्वेष के कारण अर्जुन सिंह के विरोध में सक्रिय मुहीम चला रहा है। श्रीवास्तव ने शिकायत में लिखा कि उक्त पत्र सिंह के खिलाफ नामांकन के दिन से ही अनर्गल, झूठे, मनगढ़ंत व बेबुनियाद समाचार प्रकाशित कर रहा है। पत्र अर्जुन सिंह को सुनियोजित ढग से 'सेबोटाज कर रहा है, अतः आप मोतीलाल वोरा को निर्देशित करें कि वह 'अमृत संदेश' में भ्रामक समाचार देना बंद करें, ताकि इंका प्रत्याशी की होनेवाली क्षति को रोका जा सके। महामंत्री महोदय ने यह भी याचना की है कि प्रकाशन न रुकने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करें।

अर्जुन-भक्तों ने पत्र के खरसिया स्थित संवाददाता सुनील कुमार गर्ग के नाम से प्रकाशित एक समाचार को भी इस जंग में मुद्दा बनाया है। २९ मई को प्रकाशित 'अर्जुन सिंह को स्थानीय इंका पर भरोसा नहीं, कमान बाहरी लोगों के हाथ' शीर्षक के इस समाचार के बारे में मुख्यमंत्री समर्थकों का कहना है कि उक्त समाचार गर्ग ने भेजा ही नहीं। वह अपने पक्ष में गर्ग द्वारा संपादक को लिखे पत्र और हलफनामे का उल्लेख करते हैं, जिनमें संवाददाता ने प्रकाशित समाचार को स्वयं न भेजने और उसका खंडन छापने की बात कही है।

दूसरा पक्ष : 'अमृत संदेश' का प्रकाशन प्रारंभ होने के पूर्व गोविंदलाल वोरा दैनिक 'नवभारत' के रायपुर संस्करण के संपादक और प्रबंधक थे। वह कहते हैं, "तीस साल की अखबारी जिंदगी में मैंने बहुत दौर देखे हैं।" १९७७ में इमरजेंसी के दौरान चुनाव की पूर्व वेला में तत्कालीन सूचना-प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने जब 'नवभारत' के दौरान के बंडल जब्त कराये थे, तब वोरा ही 'नवभारत' के संपादक थे। विद्याचरण की तब तूती बोलती थी, लेकिन 'नवभारत' झुका नहीं। ताजे प्रसंग पर वोरा कहते हैं, "हमने कभी किसी के विरोध का अंधा रवैया अख्तियार नहीं किया। मेरा गुनाह बस यह है कि मैंने दोनों पक्षों की रिपोर्ट छापी। मेरे पत्र ने सदैव दोनों पक्षों को स्थान दिया। चुनावी नतीजा बताता है कि हमारी खबरें व हमारा रुख सही था।"

इस मामले में केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा को खींचे जाने के मुद्दे पर उनका कहना है कि 'अमृतसंदेश' से केंद्रीय मंत्री का इसके सिवाय कोई सरोकार नहीं है कि वह मोतीलाल वोरा के अनुज हैं। वह चुटकी लेने के लहजे में टिप्पणी करते हैं—'हम हर न्यूज 'भइया' से पूछ कर तो छापने से रहे।' शिकायतें वैसे दूसरे पक्ष से उन्हें भी हैं। वह बताते हैं कि रायगढ़ में उनके संवाददाता को पार्टी के प्रेस नोट नहीं दिये गये, प्रेस वार्ताओं की सूचनाएं नहीं दी गयीं और चुनावी-विज्ञापन नहीं दिये गये।

विवादास्पद रिपोर्ट के बारे में उनका कहना है कि रिपोर्ट सुनील गर्ग ने ही भेजी थी। वह दबाव या प्रलोभन की बात नहीं करते, लेकिन १४ जून की रैली का हवाला देते हैं, जिसमें अर्जुन सिंह ने दो युवकों को अपने हाथों इंका के उल्लेखनीय प्रचार कार्य के लिए शील्ड प्रदान की। इन दो युवकों में गर्ग एक और कोई नहीं, बल्कि कल तक 'अमृत संदेश' के संवाददाता वही सुनील गर्ग हैं, जिन्होंने भ्रामक समाचार छापने से अपनी मानहानि की बात कहकर संपादक-प्रकाशकों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस दे रखा है।

इंका महामंत्री ललित श्रीवास्तव अर्जुन सिंह की ओर से पहले भी कई बार मशाल व हथियार उठा चुके हैं। पढ़ने-लिखने से ताल्लुक रखने के बावजूद इस बार उन्हें शायद पता न हो कि वह तथ्यपरक भूल कर गये हैं। चौधरी को दिये और आलाकमान तक भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि 'अमृत संदेश' गोविंद लाल वोरा व मोतीलाल वोरा के पुत्र अरविंद वोरा द्वारा प्रकाशित होता है। सचाई यह है कि भोपाल में लघु उद्योग निगम में कार्यरत अरविंद वोरा का अखबार से कोई वास्ता या लेनादेना नहीं है। कायदे से, यहां अरविंद के बजाय अरुण वोरा का जिक्र होना चाहिए था, जो 'अमृत संदेश' के दुर्ग स्थित संवाददाता हैं। वैसे, खरसिया के उपचुनाव ने अखबारों के महत्व को एक बार पुनः नये सिरे से रेखांकित करने के साथ ही अखबारों की भूमिका पर सवालिया निशान भी लगाया है। इसे अस्वस्थ प्रवृत्ति ही कहा जायेगा कि कई अखबारनवीस खरसिया में 'रिपोर्टिंग' के बजाय कैम्पेनिंग (प्रचार) करते नजर आये। राजधानी में कुकुरमुत्ते की तरह उग आये कभी-कभी निकलने-वाले अखबार खरसिया के जनमत को भले ही प्रभावित न कर सके हों, परंतु खरसिया में इंका के दफ्तर में उनके बंडल जरूर दिखायी दिये। हद तो तब हो गयी जब अपनी निष्पक्षता के लिए सुविदित एक नामी गिरामी अखबार भी मोह की बलि चढ़ गया। ताजा खबर है कि इस अखबार को रायपुर में करीब तीन साल पहले आवंटित लगभग एक एकड़ भूमि के बदले मनचाही और बेहतर शासकीय भूमि आवंटित कर दी गयी है। एक और प्रगतिशील दैनिक का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। दैनिक का एक अन्य महानगर से संस्करण तो प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसका भव्य कार्मशियल काम्प्लेक्स ऊंचे दामों पर उठ गया है। इन संदर्भों के प्ररिप्रेक्ष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने मितभाषी स्वभाव और आत्मीय बर्ताव के लिए सुपरिचित अर्जुन सिंह आनेवाले दिनों में अखबारों के साथ क्या सलूक करते हैं?

—सुधीर सक्सेना, रायपुर से

फर्जी डिग्री का धंधा

सरकार के साये में

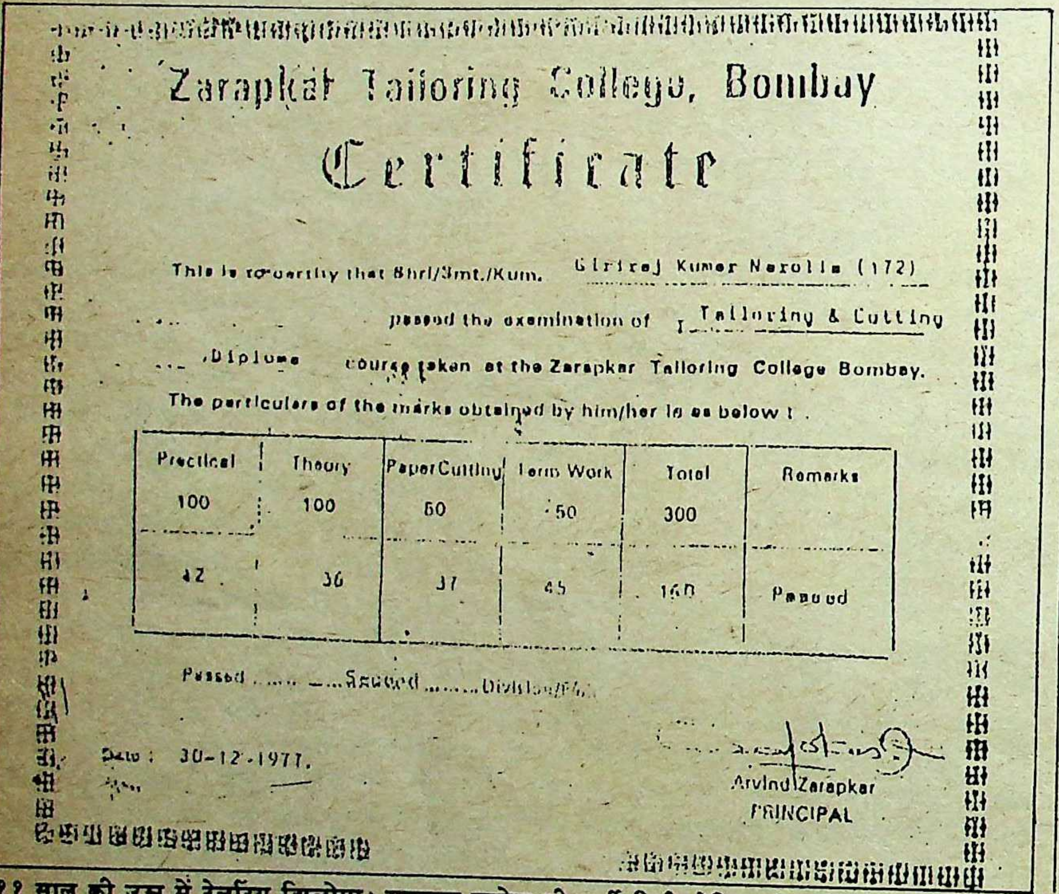

Zarapkar Tailoring College, Bombay

Certificate

This is to certify that Shri/Smt./Kum. Giriraj Kumar Narolia (172)

passed the examination of Tailoring & Cutting

Diploma course taken at the Zarapkar Tailoring College Bombay.

The particulars of the marks obtained by him/her is as below :

Practical	Theory	PaperCutting	Term Work	Total	Remarks
100	100	50	50	300	
42	36	37	45	160	Passed

Passed ....Second .... Division/...

Date : 30-12-1977.

Arvind Zarapkar
PRINCIPAL

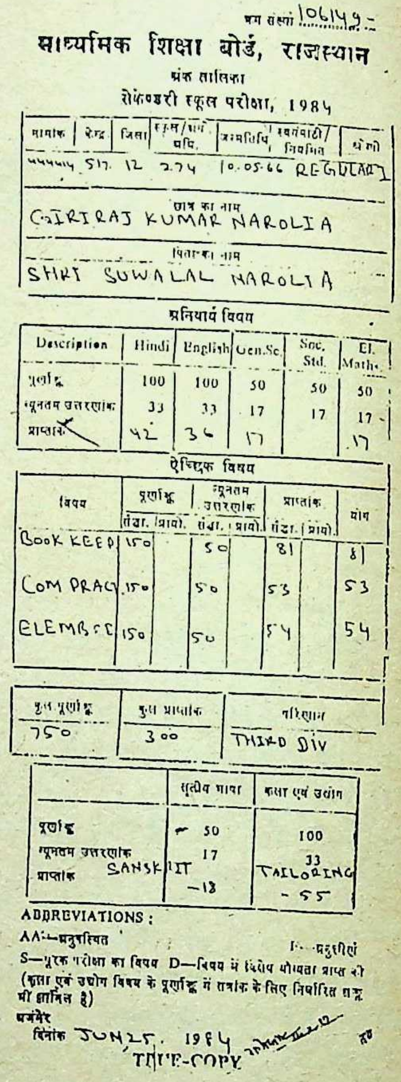

क्रम संख्या 106149

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

अंक तालिका

सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा, 1984

नामांक	केन्द्र	जिला	स्कूल/प्राइ. पवि.	जन्मतिथि	स्वयंपाठी/नियमित	श्रेणी
444444	517	12	274	10.05.66	REGULAR	

छात्र का नाम
GIRIRAJ KUMAR NAROLIA

पिता का नाम
SHRI SUWALAL NAROLIA

अनिवार्य विषय

Description	Hindi	English	Gen.Sc.	Soc. Std.	El. Maths.
पूर्णांक	100	100	50	50	50
न्यूनतम उत्तरणांक	33	33	17	17	17
प्राप्तांक	42	36	17		17

ऐच्छिक विषय

विषय	पूर्णांक		न्यूनतम उत्तरणांक		प्राप्तांक		योग
	सैद्धा.	प्रायो.	सैद्धा.	प्रायो.	सैद्धा.	प्रायो.	
BOOK KEEP	150		50		81		81
COM PRAC	150		50		53		53
ELEM B C	150		50		54		54

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	परिणाम
750	300	THIRD DIV

	तृतीय भाषा	कला एवं उद्योग
पूर्णांक	50	100
न्यूनतम उत्तरणांक	17	33
प्राप्तांक	SANSKRIT -18	TAILORING -55

ABBREVIATIONS :
AA—अनुपस्थित
F—अनुत्तीर्ण
S—पूरक परीक्षा का विषय D—विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की
(कला एवं उद्योग विषय के पूर्णांक में सत्रांक के लिए निर्धारित अंक भी शामिल है)
अजमेर
दिनांक JUN 25. 1984
TRUE-COPY

११ साल की उम्र में टेलरिंग डिप्लोमा : झरपकर कालेज की फर्जी डिग्री, देखिए अंकतालिका (दायें) में नारोलिया की जन्मतिथि

इस तथ्य ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है कि प्रदेश के करीब ४० हजार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के एक लाख ८० हजार शिक्षकों में ऐसे शिक्षकों की संख्या हजारों में है जो फर्जी डिग्रियों के बल पर शिक्षक बन बैठे हैं। रोचक तथ्य यह है कि राजस्थान सरकार के संरक्षण में यह गोरखधंधा होता रहा। इतनी बड़ी धांधली कैसे संभव हुई? 'माया' की छानबीन :

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ के तहत लड़कों के लिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक के ३६०८३ विद्यालय खोल रखे हैं, वहीं लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में २९९४ विद्यालय उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए ३६ एसटीसी विद्यालय और ३७ बीएड महाविद्यालय भी चला रखे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेष लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रशिक्षण से अभी तक केवल २३ हजार ६०० अध्यापक प्रशिक्षित कर पायी है। वैसे राज्य में एक लाख अस्सी हजार शिक्षक निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन इनमें फर्जी डिग्रियों से अध्यापक बने हजारों लोग प्रवेश कर गये हैं, जिनके रहते नयी शिक्षा नीति के लक्ष्य हासिल करने कठिन हैं।

ऐसा बताया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अध्यापक बनाने का धंधा पिछले पंद्रह वर्षों से राज्य मंत्रिमंडल के सभी शिक्षामंत्री और शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अध्यापक बने लोगों का पता पहली बार १९८१ में उस वक्त चला, जब शिक्षकों की नियुक्ति की वरीयता सूची तैयार की जा रही थी। बाद में इस भ्रष्टाचार और अवैध धंधे का और खुलासा तब हुआ, जब सन् १९८५ में पुन: नियुक्ति हेतु शिक्षकों की पात्रता सूची तैयार की जा रही थी।

राजस्थान शिक्षक संघ के महामंत्री तेजपाल शर्मा का आरोप है कि राज्य में जोशी मंत्रिमंडल में शिक्षामंत्री रहे हीरालाल देवपुरा व दामोदर दास आचार्य, तत्कालीन शिक्षा सचिव रणजीतसिंह कूमट, शासन उपसचिव (शिक्षा) एन बेलानी, सहायक शासन सचिव (शिक्षा) लक्ष्मण भंभाणी ने मिलीभगत से फर्जी प्रमाण-पत्रों के व्यवसाय तथा व्यवसायियों को प्रश्रय दिया। उनके अनुसार, २४ जुलाई, १९८७ को शिक्षा विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प-७(६) शिक्षा-३/८६ से बिहार प्रदेश शिक्षा परिषद, श्रीपालपुर पटना की द्विवर्षीय बीटीसी परीक्षा को राजस्थान की बीएसटीसी की परीक्षा के समकक्ष मान्यता दे दी। मान्यता देने में

तत्कालीन राज्य सरकार (जोशी मंत्रिमंडल) इतनी उदार रही कि मान्यता का फरमान जारी किया वर्ष १९८७ में और मान्यता प्रदान की गयी १९८५-८६ से। इस अजीब फरमान की वस्तुस्थिति जानने के लिए राजस्थान शिक्षक संघ के महामंत्री ने जब बिहार प्रदेश शिक्षा परिषद (श्रीपालपुर पटना) में अपना प्रतिनिधि भेजा, तो ज्ञात हुआ कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ऐसी (यानी बिहार की बीटीसी जैसी) किसी संस्था को मान्यता ही नहीं दी है।

'राजस्थान शिक्षक संघ के भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ के संयोजक रामनिवास शर्मा को इस जांच के दौरान पटना में ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार से अमान्य बिहार शिक्षा परिषद श्रीपालपुर के सचिव कोई डाक्टर एससी मिश्रा हैं जो दिल्ली के होटलों से अपना व्यवसाय चलाते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में जिस प्रशिक्षण स्थल श्रीपालपुर पटना का पता दिया था, वह पटना में न होकर पुनपुन नदी के किनारे दस-पंद्रह कच्चे घरों की बस्ती तक सीमित था। इन घरों में से एक छोटा, मगर पक्का मकान बिहार शिक्षा परिषद के सचिव एससी मिश्रा का था, जिसे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण केंद्र मान लिया था। शर्मा को वहां यह भी ज्ञात हुआ कि संस्था के सचिव मिश्रा ने राजस्थान के अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की निजी शिक्षण संस्थाओं को अपने से संबद्ध कर फर्जी प्रमाणपत्र देने का कारोबार चला रखा है।

इस तरह से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण और अध्ययन से प्राप्त होनेवाले प्रमाण-पत्रों के मुकाबले ऐसी संस्था को शिक्षक तैयार करने का काम सौंप दिया, जो आठ हजार रुपए में प्रशिक्षणार्थी को घर बैठे अध्ययन और प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र देती है।

राजस्थान शिक्षक संघ ने जब इस वास्तविकता को राजस्थान सरकार के सामने पेश किया, तो सरकार ने बिना किसी टीका-टिप्पणी के १३ अक्तूबर को बिहार शिक्षा परिषद, श्रीपालपुर, पटना की मान्यता रद्द कर दी। बहरहाल, इस बीच राजस्थान सरकार की पंचायत समितियों में ऐसे सैकड़ों लोगों को शिक्षक का पद हासिल हो गया, जिन्हें बिहार शिक्षा परिषद ने अपना प्रमाणपत्र बेचा था।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा परिषद, श्रीपालपुर की मान्यता रद्द करते वक्त यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संस्था जाली है, इससे सम्बद्ध कालेज फर्जी हैं और इसके द्वारा प्रचारित परीक्षा कार्यक्रम आडंबर है। नतीजा यह हुआ कि बिहार शिक्षा परिषद, श्रीपालपुर पटना से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी चाहनेवाले एक व्यक्ति ने राजस्थान उच्चन्यायालय की खंडपीठ में याचिका दायर कर सरकारी आदेश पर स्थगन की मांग की। उच्चन्यायालय के न्यायाधीश दिनकर लाल मेहता और जी०के० शर्मा ने १९ दिसंबर १९८७ को राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता को यथावत मानते हुए अध्यापक पद के लिए तुरंत विचार किये जाने का आदेश दिया।

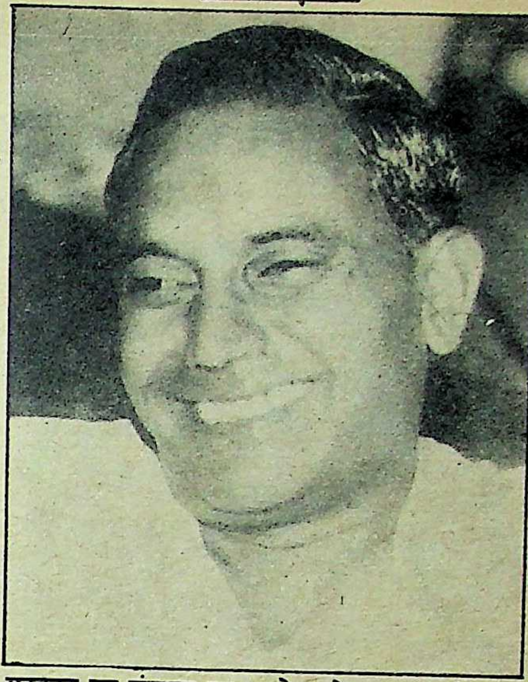

सरकार पर संरक्षण का आरोप: तेजपाल शर्मा

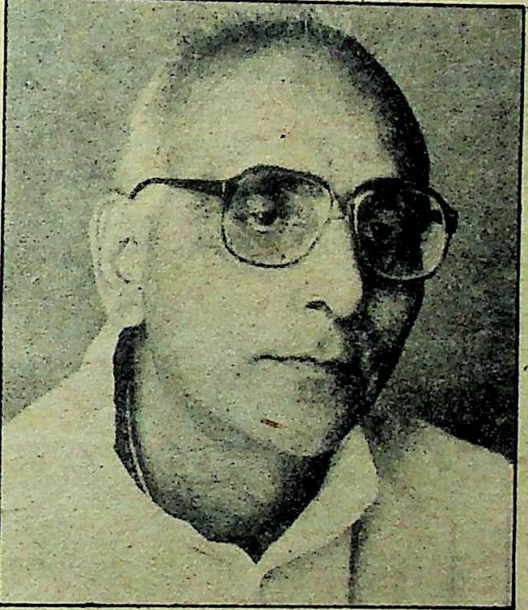

फर्जी डिग्रियों को प्रश्रय ? : दामोदरदास आचार्य

राजस्थान शिक्षक संघ के महामंत्री तेजपाल शर्मा का आरोप है कि इस प्रकार की याचिकाएं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दायर की जाती हैं। याचिका दायर करने के पीछे षड्यंत्र यह होता है कि राज्य सरकार जवाब न दे और मामला फर्जी प्रमाणपत्रों का कारोबार करनेवालों के हक में तय हो जाये। फिलवक्त राजस्थान उच्चन्यायालय में फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से नौकरी चाहनेवालों की एक सौ-दो याचिकाएं विचारार्थ मंजूर हो चुकी हैं।

बड़े-बड़ों का हाथ: फर्जी प्रमाणपत्रों के इस धंधे में पूर्व शिक्षामंत्री और अधिकारी लिप्त रहे हैं, इसका एक उदाहरण राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ग्राम सेवा वर्धा (महाराष्ट्र) की नयी तालीमी समिति ग्राम सेवा वर्धा को मान्यता देकर प्रस्तुत किया है। नयी तालीमी समिति ग्राम सेवा वर्धा १९६० तक बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थी। १९६० में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण की अनुपयोगिता महसूस करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसकी मान्यता रद्द की दी। मान्यता रद्द होने पर संस्थान बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता रद्द कर दिये जाने के बाद भी राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग समिति द्वारा दिये जानेवाले बीएसटीसी प्रमाणपत्र को ३ मई, १९८६ तक मान्य करार देता रहा।

राजस्थान शिक्षक संघ ने इस समिति की जांच के लिए जब अपने प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र भेजा, तो वहां वर्धा आश्रम के प्रमुख देशमुख पांडे ने उन्हें बताया कि मान्यता रद्द होने के बाद समिति ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समिति की देश में अन्य कोई शाखा नहीं है। इस वास्तविकता के विपरीत राजस्थान सरकार ने इस समिति की ३ मई १९८६ तक मान्यता बरकरार रखी और शिक्षक संघ के एतराज करने पर ही इसे रद्द किया। गौरतलब तथ्य यह रहा कि मान्यता रद्द करने के बाद जब ग्राम सेवा वर्धा के संचालकों ने आंशिक संशोधन के साथ पुनः मान्यता के लिए आवेदन किया, तो राजस्थान सरकार ने इस फर्जी संस्था को अप्रैल, १९८७ तक के लिए मान्य करार दे दिया। मान्यता देने की यह प्रक्रिया मंत्री स्तर तक चलकर पूरी होती है, ऐसे में कोई मंत्री इससे अनजान होने का बहाना नहीं कर सकता। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि ग्राम वर्धा की नयी तालीमी समिति की मान्यता जब महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने १९६० में समाप्त कर दी, तो राजस्थान के तथाकथित प्रशिक्षणार्थियों को योग्यता के प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कहां से प्राप्त होते रहे? राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

इसी प्रकार का एक संस्थान झरपकर सिलाई कालेज बंबई (महाराष्ट्र) में है। राजस्थान में इससे सम्बद्ध जयपुर का कथित लालबहादुर शास्त्री टेलरिंग कालेज है। इस कालेज को जयपुर के टौंक फाटक पर स्थित बताया जाता है, जबकि राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक वहां ऐसा कोई कालेज नहीं है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने इसे १९७४ से १९७८ के बीच की अवधि में मान्यता प्रदान की थी, जबकि झरपकर सिलाई कालेज बंबई को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह आज भी स्पष्ट नहीं है।

फिर, लालबहादुर शास्त्री टेलरिंग कालेज का कथित सचिव सियावर दीक्षित जयपुर में मौजूद है। आरोप है कि इस धंधे से इस सचिव ने लाखों रुपए कमाये हैं। बीकानेर में आरडी कालेज के संचालक पर भी ऐसा ही आरोप है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर घोषणा भर की थी कि प्रदेश के सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर शहर में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जयपुर के ग्राम मेड़ का

विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कालेज और डूंगरपुर का पंड्या परामर्श केंद्र ऐसे संस्थान हैं, जो बीएसटीसी और बीएड की शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त नहीं हैं। राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में उन धंधेबाजों के प्रमाणपत्र-व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं कहा जो आज भी किसी संस्था की मान्यतावाली पिछली अवधि के प्रमाणपत्र बेच रहे हैं।

शिक्षक संघ ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर शिक्षक पद हासिल कर प्रदेश के ग्राम रामकरणपुर, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में कार्यरत अध्यापक गिरिराज कुमार नारोलिया का उदाहरण तत्कालीन शिक्षामंत्री दामोदर दास आचार्य को पेश किया। अध्यापक गिरिराज कुमार नारोलिया ने १९८४ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सैकंडरी स्कूल परीक्षा १८ वर्ष की उम्र में तृतीय श्रेणी में पास की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक-तालिका में नारोलिया की जन्म तिथि १० मई, १९६६ अंकित है। इसके विपरीत बंबई के झरपकर टेलरिंग कालेज से जो प्रमाण-पत्र इन्होंने हासिल किया, उसमें द्वितीय श्रेणी के साथ जन्मतिथि ३० दिसंबर, १९७७ अंकित है। यानी अध्यापक के लिए न्यूनतम परीक्षा पास करने से सात साल पूर्व ११ वर्ष सात माह की उम्र में नारोलिया ने द्वितीय श्रेणी में टेलरिंग व कटिंग का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया था। नारोलिया की नौकरी आज भी इस हास्यास्पद प्रमाणपत्र के आधार पर बरकरार है।

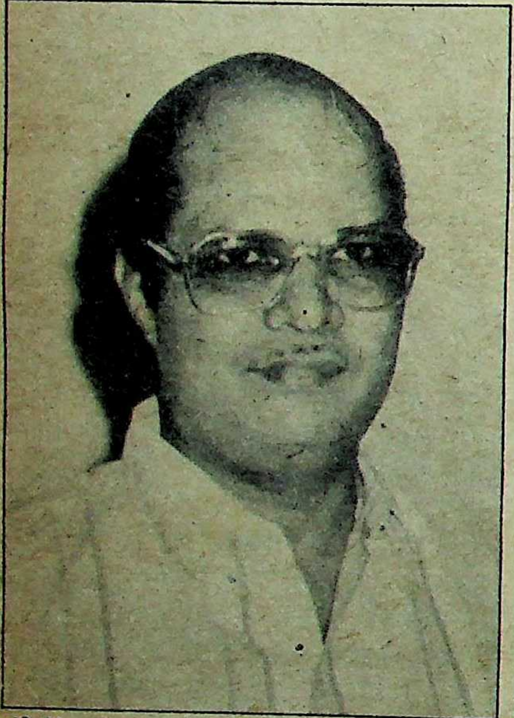

धंधे में शरीक ? : रणजीत सिंह कूमट

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से आज हालत यह है कि शिक्षा विभाग के जिन स्कूलों में १०२ लोगों को झरपकर टेलरिंग कालेज के प्रमाणपत्र के आधार पर अस्थायी रूप से पढ़ाने का काम दे दिया गया और जिन्हें झरपकर कालेज की मान्यता रद्द कर देने के कारण हटाया जाना तय था, वे राजस्थान उच्चन्यायालय से स्थगन आदेश लेकर काम पर लगे हुए हैं। राजस्थान उच्चन्यायालय के निर्णय के अनुसार जिन शिक्षकों ने वर्ष १९७८-७९ तक झरपकर टेलरिंग कालेज से प्रमाणपत्र हासिल किये हैं, उन्हें मान्य करार देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस कालेज के उक्त वर्ष के प्रमाणपत्र आज बाजार में अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं। चर्चा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी वाजिब कीमत मिलने पर आज भी झरपकर कालेज की मान्यता रद्द हो जाने के पूर्व की तिथि के प्रमाणपत्रों को वैसे ही सम्मान दे रहे हैं जैसे वर्ष १९७८-७९ के प्रमाणपत्रों को देते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ ने जयपुर जिले के जटपुरा माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक घनश्यामदास शर्मा का प्रमाणपत्र 'माया' को दिखाया। यह प्रमाणपत्र झरपकर कालेज ने ५ फरवरी '८३ में जारी किया है, जिसके आधार पर शर्मा को माध्यमिक स्कूल में अध्यापक का पद हासिल हुआ है।

फर्जी संस्थाओं की जांच : राम निवास शर्मा

दरअसल, इन फर्जी संस्थानों की दलाली के लिए राजस्थान सरकार के सचिवालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक व स्कूलों के धंधेबाज अध्यापक जिम्मेदार हैं। आरोप है कि ये लोग अधिकारियों तथा तत्कालीन शिक्षामंत्रियों के माध्यम से अपना धंधा चलाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने आश्वासन (देखिये साक्षात्कार) तो दिया है कि वह सारे मामले की बारीकी से जांच करेंगे, लेकिन देखना है कि वह सरकारी संरक्षण में पल रहे फर्जी डिग्रियों के जाल को तोड़ पाने में कितने सफल होते हैं?

—ओम सैनी

साक्षात्कार/**बुलाकीदास कल्ला**, शिक्षा मंत्री

तथ्यों की ज़ांच करूंगा

राजस्थान में फर्जी प्रमाणपत्रों के व्यवसाय के संबंध में शिक्षामंत्री बीडी कल्ला नावाकिफ हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि पूर्व सरकार के शिक्षामंत्री और अधिकारी इस संबंध में क्या कुछ करते रहे हैं। बहरहाल 'माया' ने उनसे इस संबंध में बातें कीं। प्रस्तुत हैं, वार्ता के कुछ अंश :

माया : *राजस्थान शिक्षक संघ ने फर्जी प्रमाणपत्रों के व्यवसाय के संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन दिये, राज्य सरकार उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करती ?*

कल्ला : मुझे अभी तक ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। आप पहले आदमी हैं, जिन्होंने इस संबंध में मुझे बताया है। मैं निश्चित रूप से इन तथ्यों की जांच करूंगा।

माया : *फिर तो आप पूर्व मंत्री देवपुरा और दामोदर दास आचार्य का इस मामले में क्या रूख रहा, नहीं जानते होंगे ?*

कल्ला : हां, मुझे नहीं मालूम। पर मैं अधिकारियों से जानकारी लूंगा और देखूंगा कि ऐसा होना कैसे सम्भव हुआ ?

माया : *तथ्यपूर्ण ज्ञापनों के संबंध में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है ?*

कल्ला : तथ्यों की जांच करे और उचित कार्यवाही करे। मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी जालसाजी से मुझे अब तक विभाग ने अवगत नहीं कराया है।

माया : *आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि शिक्षक संघ ने तत्कालीन शिक्षा सचिव कूमट व अन्य अधिकारियों का इस व्यवसाय में लिप्त होना बताया है।*

कल्ला : मैं तो जांच के बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/प्रशांत उपाध्याय

देश के परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवा की बात सोचनी चाहिए

पिछले वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में बिहार के अमीर सुभानी ने देश में अव्वल आकर बिहार का मान बढ़ाया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया पटना के प्रशांत ने, जो इस वर्ष प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम आये हैं। प्रशांत ने इतनी असाधारण सफलता पहली ही बार में कैसे हासिल की? प्रशांत से 'माया' की बातचीत।

"बिहार के लड़के जींस का पैंट नहीं पहनते, लड़कियों के साथ नहीं घूमते, क्लबों में डांस नहीं करते, इस मायने में भले ही बिहार के लड़कों को गावदी या पिछड़ा समझा जाये। पर बिहार के छात्रों का पढ़ायी-लिखायी के मामले में कोई जोड़ नहीं, इसे सब स्वीकारते हैं।" कहते हैं हाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में पूरे देश में अव्वल आये प्रशांत। लंबे कद, छरहरे बदन और सांवले रंग के आकर्षक व्यक्तित्व के नौजवान प्रशांत ने सचमुच अपनी असाधारण सफलता से सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का उनका यह पहला ही मौका था और बस पहली ही बाजी प्रशांत ने शानदार तरीके से मार ली।

प्रशांत के पिता डा० (मेजर) केके उपाध्याय संप्रति पटना मेडिकल कालेज के चर्मरोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और प्रशांत की मां श्रीमती रमासुंदरी पटना के मगध महिला कालेज में वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्ष।

प्रशांत की इस सफलता से जहां पूरे बिहार का मान बढ़ा है, वहीं प्रशांत के माता-पिता की भी प्रसन्नता का पारावार नहीं। श्रीमती रमासुंदरी 'माया' से भाव-विह्वल होकर कहती भी हैं कि, "मैं ईश्वर की आभारी हूं।" 'माया' के इस सवाल पर कि 'क्या आपने यह उम्मीद की थी कि प्रशांत पूरे देश में एकदम अव्वल ही आ जायेंगे' के जवाब में रमासुंदरी कहती हैं, "मैं एक शिक्षक भी हूं। कोई शिक्षक अपने छात्र से यह उम्मीद जरूर करता है कि अमुक प्रतिभावान छात्र जरूर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। पर यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि छात्र अव्वल ही आ जायेगा। प्रशांत किसी भी परीक्षा में बेहतरीन नंबर से सफल होगा, इतना विश्वास तो मुझे सदैव रहा।"

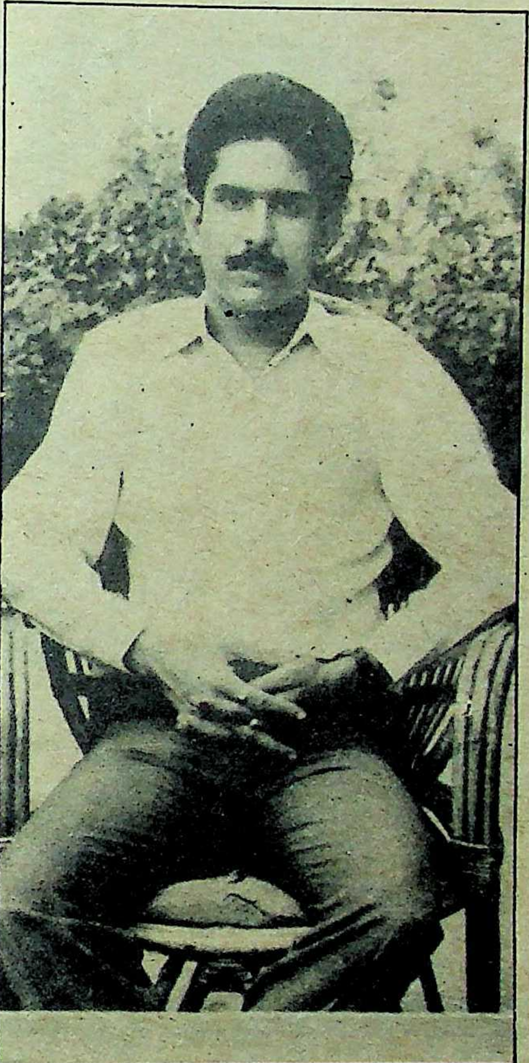

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अव्वल : प्रशांत उपाध्याय

पारिवारिक परिवेश और अपने से बड़ों की सफलता का संदर्भ किसी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में कैसे उत्साहित—प्रेरित करता है, इसके एक उदाहरण हैं प्रशांत। प्रशांत चार भाई हैं। सबसे बड़े कैप्टन शेखर उपाध्याय अभी गोरखा रेजीमेंट में जयपुर में पदारूढ़ हैं। दूसरे भाई संजय उपाध्याय स्टैंडर फार्माक्युटिकल में बतौर एरिया मैनेजर पूर्णिया में पदस्थापित हैं। तीसरे प्रभात संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता हैं। सबसे छोटे और चौथे हैं प्रशांत। प्रशांत की स्कूली पढ़ायी पटना के कानवेंट स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। आईएससी करने के लिए उन्होंने रांची के सेंट जेवियर्स कालेज में दाखिला लिया। फिर बीए करने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कालेज में चले आये और इतिहास विषय लेकर पढ़ायी शुरू की। १९८० में अव्वल दर्जे में प्रशांत बीए पास कर गये और फिर एमए में नामांकन कराया। एमए करने के दौरान वह पहली बार आईएएस की परीक्षा में बैठे और पूरे देश में अव्वल रहे।

आईएएस की तैयारी आपने कब और कैसे शुरू की? 'माया' के इस सवाल पर प्रशांत कहते हैं, "मैं कभी भी १२-१४ घंटे की पढ़ायी करनेवाला छात्र नहीं रहा। हां नियमित रूप से पांच-छह घंटे रोज पढ़ता रहा। दरअसल हर सुबह मैं तय कर लेता कि आज अमुक टापिक को पूरा कर लेना है। सो वह टापिक तैयार करने में चार-पांच घंटे लगे तो भी ठीक और दस-बारह घंटे लगे तो भी ठीक।"

आईएएस की परीक्षा में बैठने की तैयारी मैंने १९८६ के अगस्त महीने में शुरू की। पहले समाजशास्त्र को पढ़कर पूरा किया, फिर दो माह तक इतिहास की पढ़ायी की और फिर १९८७ के जुलाई महीने में 'मेन्स' (मुख्य परीक्षा) के लिए पढ़ायी शुरू की। परीक्षा की तैयारी में इतिहास व समाजशास्त्र की किताबों के अतिरिक्त भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित 'इंडिया इयर बुक', 'योजना' और 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका तथा 'इंडियन फारेन रिव्यू' नामक पत्रिका भी देखते रहे। इसके अतिरिक्त एनसीआरटी की किताबों का सूक्ष्म अध्ययन किया। फिर सेंट स्टीफेंस कालेज की लायब्रेरी में नियमित पढ़ायी की। जनरल स्टडीज में मुझे ६०० में ४२८ अंक मिले। दरअसल परीक्षा में मेरे सफल होने का कारण इतिहास या समाजशास्त्र नहीं, बल्कि जनरल स्टडीज़ ही था। आमतौर पर आईएएस की परीक्षा में जिन्हें बेहतरीन अंक मिलते हैं, उन्हें अपने गृह प्रांत में पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाती है। पर प्रशांत ने अपने गृह प्रांत बिहार में रहना स्वीकार नहीं किया है। प्रशांत इस संबंध में 'माया' से कहते हैं, "हर व्यक्ति को चाहे वह जिस किसी क्षेत्र में हो, देश के परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवा की बात सोचनी चाहिए।"

एक आईएएस अधिकारी के रूप में आप जिस किसी प्रांत में जायेंगे, वहां किस किस्म का सुधार लाने की सोचते हैं? 'माया' के इस सवाल पर प्रशांत कहते हैं, "अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने मन से प्रशासनिक सुधार की बात सोचता है, तो यह महज खामखयाली है। विधायिका सर्वोपरि है और अधिकारी उसके निर्देश का बस पालक है और कुछ नहीं।"

—विकास कुमार झा

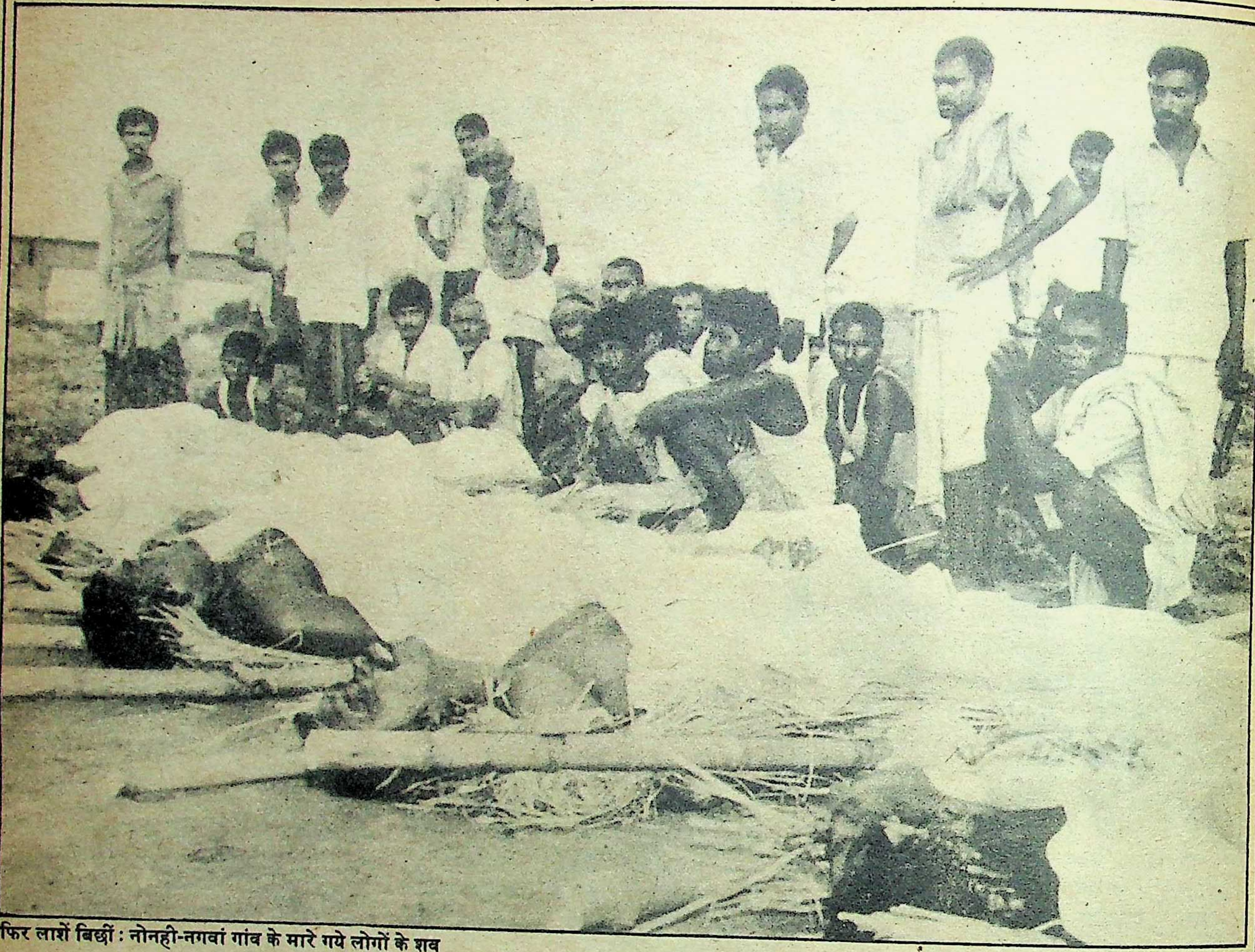

फिर लाशें बिछीं : नोनही-नगवां गांव के मारे गये लोगों के शव

नोनही-नगवां नरसंहार

जहानाबाद : भाग्य में रक्तपात

जहानाबाद में १६ जून की रात में एक बार फिर १९ लाशें बिछ गयीं। इस बार नोनही-नगवां गांव के हरिजन सामूहिक नरसंहार के शिकार हुए। तीन दिन बाद ही इसी जिले के खरका गांव के नरहन टोला में चार यादव गोलियों से उड़ा दिये गये। विडंबना यह है कि जहानाबाद में आये दिन रक्तपात हो रहा है, लेकिन सरकार मृतकों के परिजनों को बीस-बीस हजार रुपए मुआवजा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने इलाके के सभी सामंतों के हथियार जब्त करने की घोषणा की है, लेकिन क्या सरकार ऐसा करने में कामयाब हो सकेगी? क्या इससे रक्तपात रुक जायेगा? जहानाबाद में आखिर आये-दिन ये हत्याकांड क्यों हो रहे हैं। 'माया' की तफ्तीश :

विधवा मालती अपने सात वर्षीय बेटे उमेश के शव पर पछाड़ें मारकर रो रही है। उस छोटी सी अरथी पर उसके इकलौते बेटे के साथ उसकी डेढ़ वर्षीया बेटी का भी शव छलनी पड़ा है और उसके बगल में पति लाल दास पासवान की लाश। मालती बिलकुल बदहवास है। कभी मरे पड़े दोनों बच्चों का मुंह देखती है, तो कभी अपने पति का निर्जीव चेहरा। पास खड़े एक आदमी ने असीम करुणा से कहा, "क्या देख रही हो, अब कुछ बचा भी है क्या?"

उस जगह उन्नीस लाशें कतारबद्ध रखी थीं और चारों तरफ विलाप के स्वर थे। जहानाबाद के श्मशान में रखी ये लाशें जहानाबाद से तकरीबन सात किलोमीटर पूरब स्थित गांव नोनही-नगवां से अंतिम क्रिया के लिए लायी गयी थीं। वह १७ जून की रात थी। ठीक एक दिन पहले यानी १६ को नोनही-नगवां गांव में यह भीषण रक्तपात हुआ था।

जहानाबाद के निर्मम भाग्य में सिर्फ रक्तपात ही तो लिखा है। निरीह लाशों के रक्त का भोग करना जहानाबाद के गांवों की बदनसीब मिट्टी की नियति है। नक्सली विप्लवी जहां एक ओर अपना

बच्चों को भी नहीं छोड़ा : मालती का नन्हा बेटा उमेश और डेढ़ वर्षीय बेटी

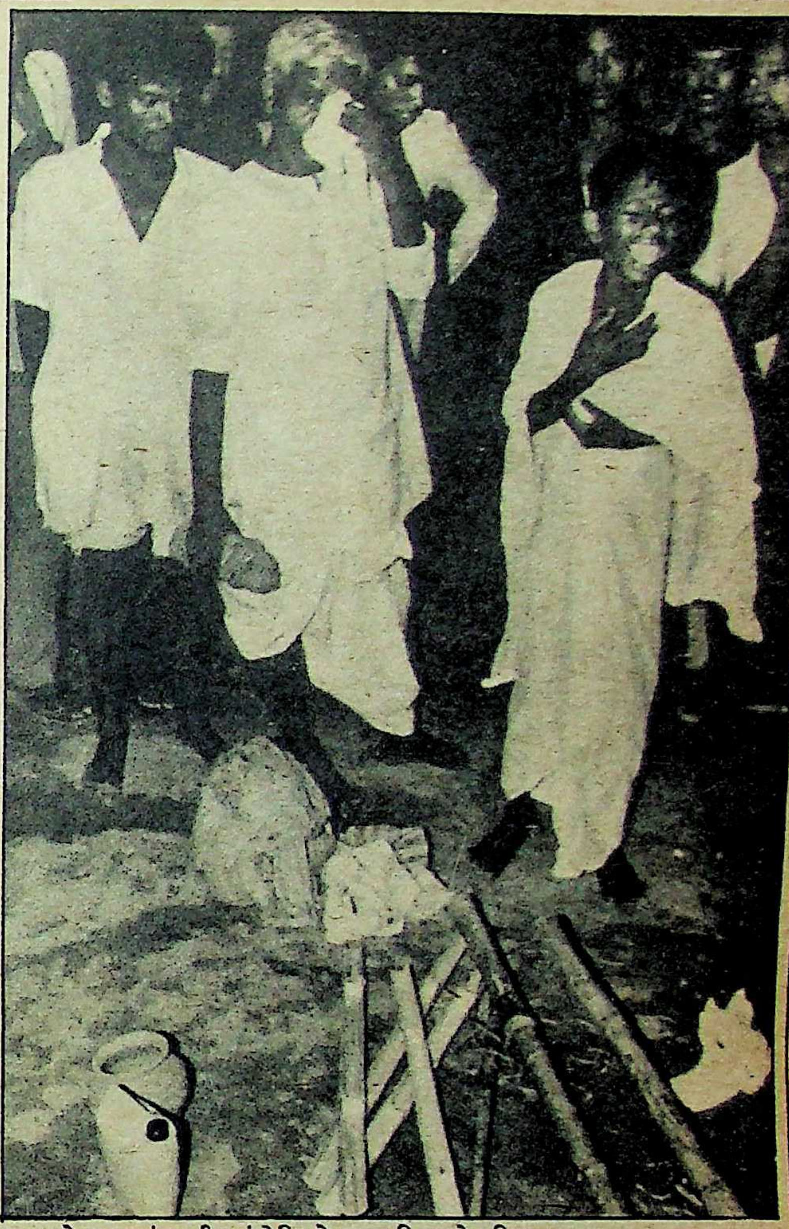

कब रुकेगा नरसंहार ? : अंत्येष्टि के समय बिलखते परिजन

खेल खेल रहे हैं, तो जातीय सेनाएं व पुलिस दूसरी ओर अपना खेल। ऐसे में जहानाबाद की मुक्तिकामी सिहरी स्तब्ध आबादी कहां जाये, कहां है अंत इसका ? पंजाब की तरह बिहार के इस छोटे से जिले में लगभग हर माह लाशों का ढेर लग रहा है। अखबारों में सुर्खियां लगती हैं। केंद्र से लेकर पटना तक के नेता-अधिकारी घटनास्थल पर दौड़ जाते हैं। जो इस दुनिया से चले गये, उनके बारे में क्या सोचना ? पर जो यहां जीवित हैं, उनके बारे में भी सोचने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। मालती विधवा हो गयी, संतानविहीन हो गयी। उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं कि अब वह कैसे जिंदगी गुजारेगी, कहां आश्रय पायेगी ? १६ जून के रक्तपात में मौत के घाट उतरे कारूं मोची की पत्नी सार्वित्री का क्या होगा या फिर मृतक सुगंबर मोची, फगुनी मोची, शिबू मोची, चंद्रदेव, रघुदास, बालदेव, लालदास मोची, रवींद्र मोची, देवचरण दास, कारादास, गंगादास, छोटे दास आदि के परिवार की दशा अब क्या होगी ? इसके बारे में न तो सरकार और न ही नोनही-नगवां जाकर मृतकों के परिजन से मिले देश के तथाकथित दिग्गज विपक्षी नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग ही सोचने को तैयार हैं। बस, पारंपरिक रूप से हंगामा इतना ही मचा है कि नोनही-नगवां में इतना भीषण नरसंहार कैसे हुआ ? और सचमुच बहुत बुरा हुआ। दिल-ही-दिल में मृतकों के परिजन से लेकर तमाम राजनेता व अधिकारी भी समझते हैं कि इस अफरातफरी का परिणाम बिहार में पूर्व के रक्तपातों की भांति कुछ भी नहीं निकलनेवाला, सो भागते भूत की लंगोटी ही सही। सरकार ने मृतकों के परिजनों को बतौर मुआवजे के जो बीस-बीस हजार रुपए थमाये, उसे सबने लिया। इसके आगे कुछ मिलने से भी रहा। जानमाल की रक्षा की गारंटी का सवाल ही कहां ?

जहानाबाद में क़ई वर्षों से जीवित लोग किस मुर्दा हाल में हैं और यह मुर्दानगी कैसे छंट सकती है, इस पर अगर माथापच्ची की गयी होती, तो आज जहानाबाद बिहार का 'लाश-घर' नहीं बनता।

यों हुआ हादसा : "निकलो! दरवाजा खोलो!" यह हिंस्त्र स्वरों का समूह था। जहानाबाद जिले के काको थाने के नोनही-नगवां गांव में रात के लगभग साढ़े ग्यारह बजे की निस्तब्धता को तीस-चालीस सशस्त्र लोगों की आवाज ने भंग कर दिया था। हरिजनों के इस टोले में पहले तो लोगों को लगा कि शायद चोर आ गये हैं। पर अगले ही पल सशस्त्र दल ने एक-एक को खींच कर गोली से भूनना शुरू कर दिया। देखते-देखते पूरा गांव लाशों से बिछ गया। नोनही गांव में सत्रह लोग गोली के शिकार हुए थे। सशस्त्र दल अंधेरे में भागते हुए सिर्फ आधा किलोमीटर आगे स्थित नगवां टोला में कुछ मिनटों के लिए रुका और वहां भी दो हरिजमों को गोली मार आगे बढ़ गया। नोनही कोई बहुत बड़ा गांव नहीं। इस गांव का मूल नाम है—नोनही, और गांव से लगभग ५०० गज की दूरी पर हरिजनों का टोला है, जिसका नाम हरिजनों ने भागलपुर टोला रखा हुआ है। इस गांव में तकरीबन ७०-७५ घर भूमिहार, दस घर कायस्थ, दस-पंद्रह घर कहार और कुछ घर साहु-बनिया आदि के हैं। नोनही के इर्द-गिर्द के टिकुलियापर, सुदोबीघा, चंदौरा, नगमा टोला, हामीनगर सफेपुर और खालिसपुर आदि गांव यादवबहुल हैं। गांव के यादव-भूमिहारों की प्रमुख आजीविका कृषि है। गांव के हरिजन मजदूरी कर

अब बचा ही क्या है ? : हादसे के बाद नोनही-नगवां गांव की औरतें

रस्म अदायगी : नरसंहार के बाद पहुंची पुलिस

सरकार कब चेतेगी ? : नोनही-नगवां कांड के खिलाफ प्रदर्शन

जीवन यापन करते हैं।

असलियत क्या है ? : १६ जून की रात गांव के हरिजन टोले में यह नरसंहार क्यों हुआ ? इसको लेकर कई किस्म के किस्से उभरे। विभिन्न संगठनों द्वारा घटना स्थल की यात्रा के पश्चात दी गयी जांच-रपटों की मानो बाढ़ सी आ गयी। सबके अपने-अपने तर्क व दावे थे। शुरू में यह खबर गर्म हुई कि इंडियन पीपुल्स फ्रंट और मजदूर किसान संग्राम समिति (अरविंद गुट) के आपसी मतभेदों के कारण यह हिंसक घटना हुई। इस खबर का खंडन करते हुए कई विपक्षी नेताओं व नक्सली संगठनों ने बयान जारी कर कहा कि सरकार अपने बचाव के लिए ऐसे किस्से उड़वा रही है। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने अपनी जांच रपट में कहा कि यह नरसंहार नक्सली संगठनों में मनमुटाव के कारण नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के कुख्यात हरेराम यादव के गिरोह से मिलकर नोनही के सामंतों ने कराया। फ्रंट की रपट में कहा गया कि हरेराम यादव को उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामबिलास पासवान ने कहा कि यह हादसा सामंती जुल्म की परिणति है। इंका के बागी नेता डा० जगन्नाथ मिश्र ने नोनही से लौटकर बयान दिया कि न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ। प्रदेश की सरकार के लिए यह घटना एक गंभीर चुनौती है। बहरहाल, वादों-प्रतिवादों की झडी लगी रही। पर इस नरसंहार के पीछे छिपी तल्ख सचाई आखिर क्या थी ? इस नरसंहार में मारे गये लालदास पासवान की विधवा मालती ने यह बयान दिया कि नोनही के प्रमुख सामंत राजनंदन सिंह से लालदास ने कुछ समय पूर्व लगभग दो हजार रुपए कर्ज लिये थे। इस घटना के ठीक दो-तीन दिन पहले राजनंदन ने खेत में पड़ा लालदास का अठारह मन गेहूं यह कहकर रोक दिया कि पहले कर्ज के पैसे सूद सहित वापस करो, फिर गेहूं ले जाओ। मालती के मुताबिक इसी बात को लेकर राजनंदन सिंह से उसके पति की काफी कहा-सुनी हो गयी थी। क्या लालदास की विधवा का यह तर्क सच है ? जहानाबाद के काको थाने के तहत के ही एक पंचायत के मुखिया का कहना है कि इस कांड के पीछे अकेले यही बात नहीं हो सकती। इस इलाके के भूमिहार सामंतों ने एक-दो बार छोड़कर कभी भी इस तरह का रक्तपात नहीं किया। नोनही के सामंत राजनंदन सिंह भी भूमिहार ही हैं। पिछले वर्षों में अनगिनत प्रमुख भूमिहार सामंत मारे गये, उसके बावजूद प्रतिशोध स्वरूप कहीं कोई खून-खराबा नहीं हुआ। धोसी प्रखंड के प्रमुख रामानंद सिंह, धोसी प्रखंड के ही देवरा पंचायत के मुखिया रामसागर सिंह, काको प्रखंड के तहत पाली पंचायत के मुखिया राजेंद्र सिंह, करपी प्रखंड के तहत ख्याल पंचायत के मुखिया दीनानाथ सिंह आदि की नृशंस हत्या हो गयी, पर इन हत्याओं के एवज में कभी रक्तपात नहीं हुआ। ये सभी मुखिया भूमिहार जाति के ही थे।

बहरहाल, यह तर्क अपनी जगह पर सही भी हो सकता है। पर नोनही-नगवां कांड के प्रसंग में यह

तर्क बहुत समीचीन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि नोनही के सामंत राजनंदन सिंह से हरिजनों का तनाव इस घटना के पीछे एक अहम कारण अवश्य है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजनंदन के पुत्र का संबंध भी 'मजदूर किसान संग्राम समिति' से रहा है। पर बगल के गांव खालिसपुर के यादवों की नोनही के हरिजनों से सख्त नाराजगी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यादवों की 'लोरिक सेना' व नोनही के सामंत के संयुक्त प्रयास से यह खूनी वाकया हुआ। कानू सान्याल गुट के सीपीएमएल नेता व हायाघाट से विधायक उमाधर सिंह की यह टिप्पणी उपयुक्त थी कि यह कांड नक्सली संगठनों में सामंती घुसपैठ से उपजी विकृति का परिणाम है।

खालिसपुर के यादव नोनही के हरिजनों से क्यों नाराज थे यह एक अलग किस्सा है। खालिसपुर गांव में नक्सली संगठनों के दो गुट सक्रिय हैं। गांव के कोइरी, मुसलमान व हरिजनों के एक गुट को नेतृत्व देता है—कोइरी जाति के आईपीएफ व किसान सभा से सम्बद्ध अवध सिंह तथा यादव गुट का मोर्चा गांव में कुख्यात अपराधी राजदेव यादव संभालता रहा है। विगत अप्रैल माह में खालिसपुर के मेंघनाथ महतो व एक अन्य की जब हत्या हो गयी, तो गांव में यादवों के खिलाफ आक्रोश उभरा। फिर 'बिहार प्रदेश किसान सभा' के बैनर के तहत खालिसपुर के ग्रामीण यादवों के आतंक के विरुद्ध जुलूस लेकर जहानाबाद के जिलाधिकारी के पास जा रहे थे कि जहानाबाद स्टेशन के समीप राजदेव यादव के एक दायें हाथ कहे जानेवाले अपराधी रामजी यादव ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका। बस उत्तेजित भीड़ ने रामजी यादव की इतनी पिटायी की कि पटना में अस्पताल तक आते ही उसकी मृत्यु हो गयी। रामजी यादव की मौत से इलाके के तमाम यादव बेहद गुस्से में आ गये। यादवों को उबलते देख खालिसपुर गांव के अधिकांश गैरयादव गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। बिहार प्रदेश किसान सभा की ओर से फिर खालिसपुर से भागे हुए लोगों को ले जाकर बसाने की पहल हुई। खालिसपुर गांव के मसले पर किसान सभा की इस सक्रिय मुहिम में नोनही-नगवां के हरिजन भी राजनंदन मोची के नेतृत्व में काफी सक्रिय थे और किसान सभा के हर जुलूस में एकमुश्त शरीक भी हो रहे थे। खालिसपुर, टिकुलियापुर और सुदोबीघा आदि यादवबहुल गांव के यादव नोनही नगवां के हरिजनों की अपने विरुद्ध सक्रियता से काफी नाराज हुए। इस नाराजगी के तहत ही यादवों ने नोनही कांड के पूर्व जहानाबाद के तहत ही गोलखपुर गांव के पांच हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद काको प्रखंड के ही एक गांव जहरबीघा पर भी हिंसक धावा किया। स्थानीय लोगों के अनुसार जहरबीघा गांव पर रामाशीष यादव के गिरोह ने हमला किया था। नोनही-नगवां के लोगों के मुताबिक रक्तपात के एक-दो दिन पूर्व यादवों की 'लोरिक सेना' के प्रधान रामानंद यादव को नोनही के आसपास सक्रिय देखा गया था।

कम्युनिस्ट सांसद रामाश्रय सिंह

जहानाबाद के इंका विधायक असगर हुसैन 'माया' से कहते हैं, "सिर्फ नोनही-नगवां ही नहीं गोलखपुर तथा जहरबीघा कांड के पीछे जहानाबाद के कम्युनिस्ट सांसद रामाश्रय सिंह की रणनीति है।" दूसरी तरफ, रामाश्रय सिंह नोनही-नगवां नरसंहार के पीछे इंका विधायक जगदीश शर्मा और असगर हुसैन के हाथ होने का आरोप लगाते हैं।

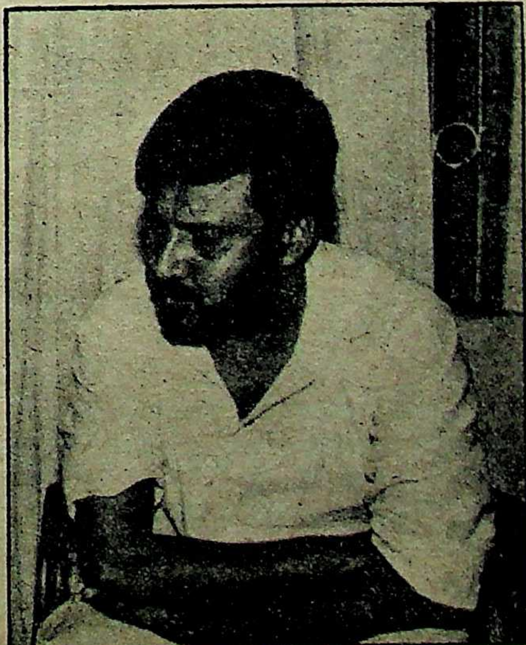

इंका विधायक असगर हुसैन

हिंसा की राजनीति: जहानाबाद के इंका विधायक असगर हुसैन 'माया' से कहते हैं, "सिर्फ नोनही-नगवां ही नहीं गोलखपुर तथा जहरबीघा कांड के पीछे जहानाबाद के कम्युनिस्ट सांसद रामाश्रय सिंह की रणनीति है। रामाश्रय सिंह अपने स्वजातीय यादवों को बरगला कर हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। आम चुनाव के पूर्व वह पूरे जहानाबाद में एक आतंक खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसी दम पर फिर वह चुनाव जीत सकें। खुद सांसद रामाश्रय सिंह पर हत्या के चार-पांच संगीन मामले चल रहे हैं। १९८१ में, वह गुंडा ऐक्ट में भी बंद किये गये थे। रामाश्रय ही 'लोरिक सेना' के संरक्षक हैं।" दूसरी तरफ रामाश्रय सिंह नोनही-नगवां नरसंहार के पीछे इंका विधायक जगदीश शर्मा और असगर हुसैन के हाथ होने के आरोप लगाते हैं।

नरसंहार के तत्काल बाद घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने जब यह घोषणा की कि इलाके के सामंतों के सभी हथियार जब्त कर लिये जायेंगे, तो आश्चर्यजनक रूप से यहां तक कि कुछ नक्सली संगठनों के नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति की कि सभी सामंतों के हथियार जब्त करना अनुचित बात होगी। सामंतों के खिलाफ आंख मूंदकर लड़ायी लड़ने का झंडा लहरानेवाले नक्सली भी कितने पतनमुखी हो चुके हैं, यह जाहिर हो गया। नोनही कांड के चार दिन बाद केंद्रीय राज्यमंत्री चिंतामणि पाणिग्रही भी आये और रस्म अदायगी कर चले गए।

नोनही-नगवां की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि फिर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाने के तहत खरका गांव के नरहन टोला में १९ जून को चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस कांड में मारे गये सभी लोग यादव ही थे—मोहर यादव, रामेश्वर यादव, जनक यादव और चंद्रदीप यादव। नरहन कांड यादवों की आपसी लड़ायी का नतीजा था। २० दिसंबर, १९८७ को कोरिया चातर कांड में संलग्न इंद्रदेव यादव घटना के छह दिन पहले जेल से जमानत पर छूटा और नरहन में लाशें बिछा दीं और फिर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया। इस क्षेत्र में इंद्रदेव यादव व पीपा यादव के बीच खूनी मुठभेड़ में बारह से अधिक लोग प्राण गंवा चुके हैं।

सवाल फिर वही कि यह सब कब तक? जहानाबाद तो हादसों का स्थायी पर्याय बन चुका है। ४ जनवरी, १९८८ को मखदुमपुर थाने के तहत विष्णुगंज पुलिस चौकी से नक्सलियों ने न सिर्फ हथियार लूटे, बल्कि हमला कर चार पुलिसकर्मियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। कभी नक्सली, कभी जातीय सेनाओं, कभी पुलिस, तो कभी सामंतों का तांडव कब तक जहानाबाद में होगा—इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जहानाबाद के भीत—त्रस्त लोग सांस लेने का रास्ता तलाश रहे हैं। क्या कोई रास्ता मिलेगा उन्हें?

—विकास कुमार झा

कृष्ण लाल को अपनी बिटिया की बड़ी चिन्ता है....
तभी तो उन्होंने लड़के वालों को
दो साल ठहरने के लिए तैयार कर लिया!

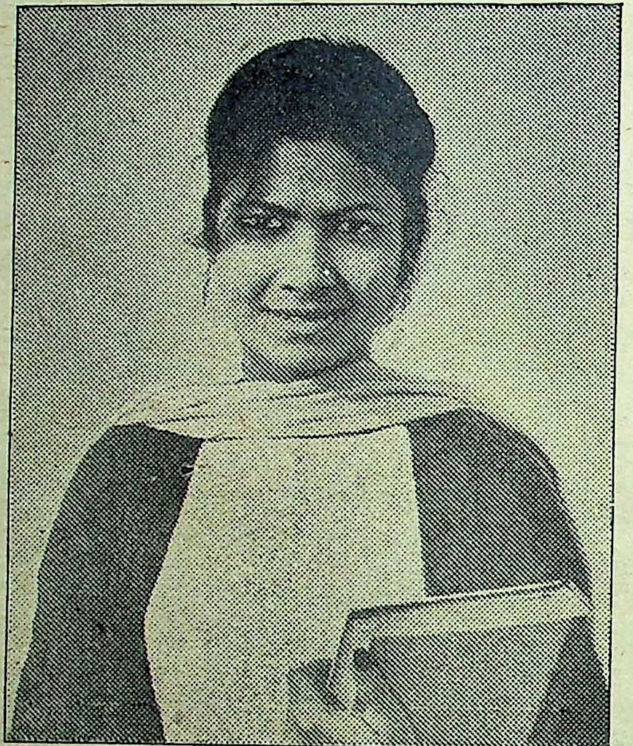

कृष्ण लाल के सभी दोस्त और रिश्तेदार हैरान हैं कि भला उन्होंने बेटी की शादी दो साल के लिए क्यों टाल दी?

लेकिन कृष्ण लाल ने अपनी लाड़ली बिटिया के हित की बात की है।

उनकी बिटिया अभी 16 बरस की है और वह अभी विवाह तथा मातृत्व की ज़िम्मेदारी सम्हालने लायक नहीं है। और फिर कृष्ण लाल अपनी बेटी को हंसने-खेलने और पढ़ने का पूरा मौका देना चाहते हैं।

एक समझदार पिता होने का परिचय दिया है कृष्ण लाल ने। वे जानते हैं लड़की की शादी अठारह साल और लड़के की शादी इक्कीस साल से पहले करना उन पर बहुत बड़ा बोझ डालना है। बच्चों को समझदार वयस्क बनने दें ताकि वे अपना भविष्य स्वस्थ और सुखद रूप से बिता सकें।

डाक्टर की सलाह मानिए :

डाक्टरों का कहना है कि लड़की के शरीर का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता रहता है। वह 15-16 साल में जवान ज़रूर दिखती है लेकिन गर्भाशय और डिम्ब ग्रन्थियों का विकास 18 वर्ष तक होता रहता है। अगर लड़की 18 वर्ष से कम आयु में माँ बने तो ये मुश्किलें सामने आती हैं :

1. लड़की के शरीर का विकास रुक जाता है।
2. 18 वर्ष से कम उम्र माँ की सन्तान कमज़ोर और कम वज़न की पैदा होती है।
3. ऐसी कमज़ोर या कम वज़न संतान की बहुधा मृत्यु हो जाती है।
4. क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र में कुछ प्रजनन अंगों जैसे गर्भाशय और डिंब ग्रंथियों का विकास पूर्ण नहीं होता इसलिए अक्सर गर्भपात हो जाता है। माँ बनने में भी कठिनाइयाँ आती हैं।
5. पैलविस का पूर्ण विकास 18 साल से पहले नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे का सिर उसकी तुलना में बड़ा पड़ सकता है। प्रसव में बाधा से अन्दरूनी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मूत्राशय या मलाशय में कमजोरी पैदा हो जाती है।
6. कम उम्र में यौन-सम्बन्ध से गर्भाशय-मुख में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह भारतीय महिलाओं में कैंसर का मुख्य कारण है।

याद रखिए:बच्ची के बच्चा होना उसके साथ घोर अन्याय है।
अठारह वर्ष से पहले लड़की और इक्कीस वर्ष से कम लड़के की शादी कानूनन अपराध है।

और जानकारी और मुफ़्त पत्रिका के लिए इस पते पर लिखिए:पोस्ट बाक्स नं. 5420 नई दिल्ली 110011

davp 88/150

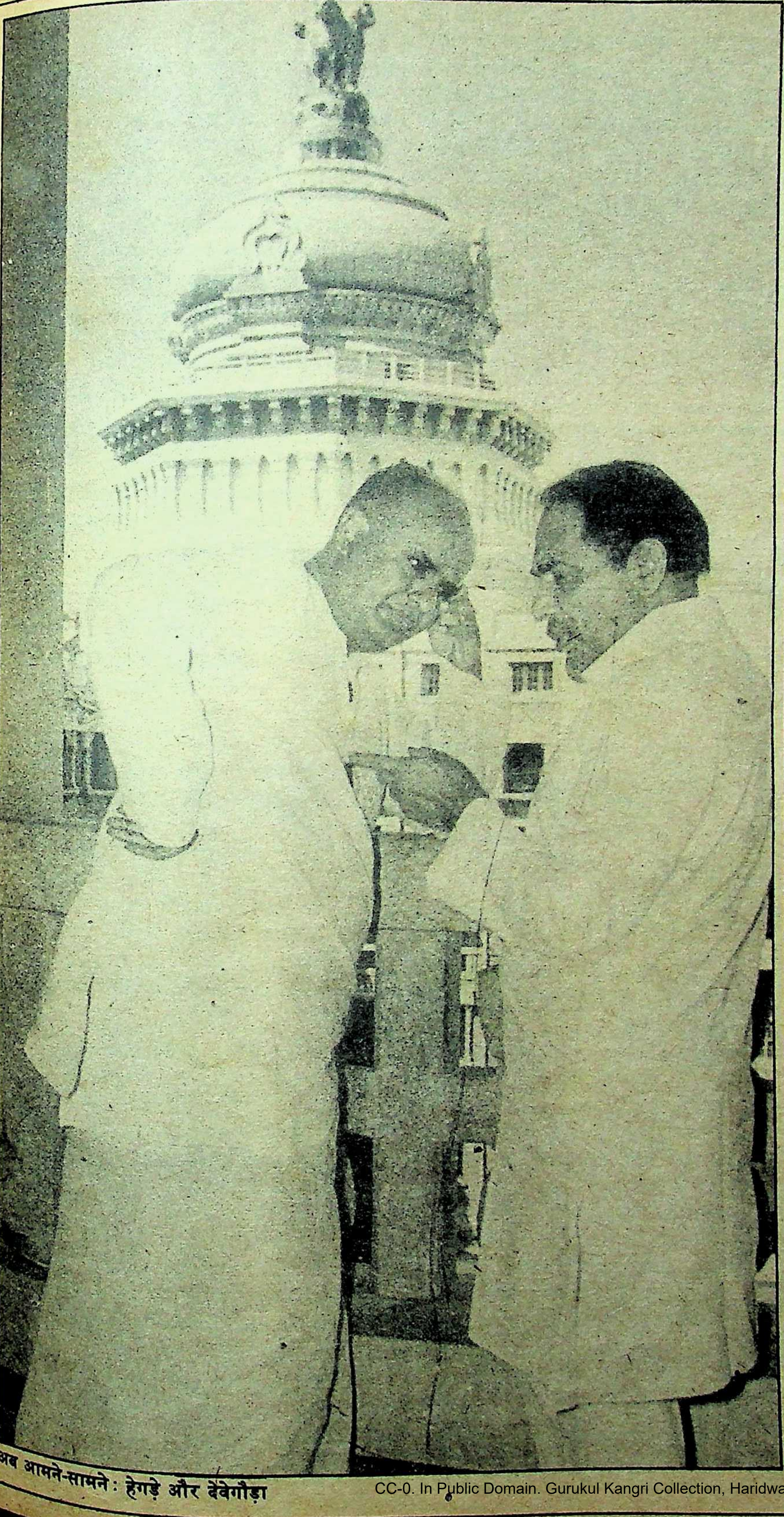

अब आमने-सामने : हेगड़े और देवेगौड़ा

जनता पार्टी

विभाजन के कगार पर

एक ओर हेगड़े सरकार के वरिष्ठ मंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर हेगड़े के विरुद्ध प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर प्रदेश जनता पार्टी में बढ़ते कलह ने यह हालात पैदा कर दिये हैं कि छह जून को हुए विधान परिषद चुनावों में जनता पार्टी के दो विद्रोही प्रत्याशी धड़ल्ले से जीत गये और १९ जून को विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक वर्ग के छह स्थानों के चुनाव में जनता पार्टी एक भी स्थान नहीं जीत सकी। देवेगौड़ा हेगड़े से नाराज क्यों हैं? क्या हेगड़े अपनी कुरसी बचा सकेंगे?

२८ अप्रैल को हेगड़े मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री एचडी देवेगौड़ा के त्यागपत्र के साथ ही कर्नाटक जनता पार्टी पर सकट के बादल घिर आये थे, जो लगातार गहराते चले जा रहे हैं। राज्य में वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों को देखकर लगता है कि राज्य जनता पार्टी में विघटन को शायद ही कोई रोक पाये।

इन राजनीतिक गतिविधियों की झलक जून में हुए विधान परिषद के चुनावों में काफी-कुछ देखने को मिलती है। अभी १९ जून को हुए विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक वर्ग की सभी ६ सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवार धराशायी हो गये। इसके पहले ६ जून को हुए चुनाव में भी पार्टी के दो असंतुष्ट उम्मीदवार जीत चुके हैं। चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों की हार तथा विपक्षी और विद्रोहियों की जीत पार्टी के अंदर बढ़ते हुए कलह को ही उजागर करती है।

असंतुष्टों के नेता एचडी देवेगौड़ा ने हेगड़े सरकार की कारगुजारियों से राज्य की जनता को अवगत कराने के लिए ज़िला व तालुका स्तर पर जन सभाओं को संबोधित करने का अभियान चला दिया

है। उन्हें सुनने के लिए उसी प्रकार भीड़ उमड़ पड़ती है जैसे कभी मेनका गांधी को सुनने के लिए उमड़ती थी। देवेगौड़ा ने हेगड़े का तख्ता पलटने के लिए किसानों का सहारा लेने की योजना बना ली है। वह जनसभाओं में हेगड़े सरकार की खुली आलोचना करते हुए राज्य के किसानों को आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देवेगौड़ा अपनी बगावत के लिए सफायी देते हुए कहते हैं कि किसानों के प्रति अन्याय उनसे सहन नहीं होता। सरकार ने सिंचाई योजनाओं के लिए ३०० करोड़ रुपए अलाट करने की बात कही थी, परंतु बाद में मुकर गयी, इसीलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। देवेगौड़ा का कहना है कि हेगड़े सरकार को गिराने का उनका कोई मकसद नहीं हैं, न ही वह हेगड़े के नेतृत्व के प्रति कोई शिकायत रखते हैं। उनका विरोध हेगड़े के काम करने के ढंग से है, हेगड़े की स्वयं की नीतियों से है, पार्टी में उनकी तानाशाही से है।

विधान परिषद के हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के सामने तीन स्थानों पर असंतुष्टों ने अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, जिनमें से एम विवेकानंदैया तथा केबी पिल्लप्पा विजयी हुए और तीसरे उम्मीदवार सिद्दरामैया बहुत ही कम अंतर से हारे। पार्टी पर बागी उम्मीदवारों की इस विजय के बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े विधान सभा भंग करने के पक्ष में हैं तथा वह अपने कानूनी सलाहकारों से इस विषय में विचार-विमर्श कर रहे हैं। बाद में हेगड़े ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय १३ जून को हेगड़े ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि विधानसभा तभी भंग होगी, जब सरकार अल्पमत में आ जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता सरकार को गिराकर यदि राज्य में दूसरी सरकार बनती है, तो वह सरकार आंध्र प्रदेश की एन भास्कर राव सरकार, केंद्र में चरण सिंह की सरकार और कश्मीर में जीएम शाह की सरकार के तुल्य होगी और कांग्रेस-इ के हाथों में खेलने को मजबूर होगी।

पार्टी में वफादारों और असंतुष्टों के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि यदि दलबदल विरोधी कानून का डर न होता, तो जनता पार्टी दो माह पूर्व ही विभाजित हो जाती, किंतु कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि वह अपने कार्यकाल से २० माह पूर्व ही विधानसभा की सदस्यता खो दे।

संकट पैदा क्यों हुआ ? : कर्नाटक जनता पार्टी में आज जो संकट की स्थिति पैदा हुई है, उसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। १९८३ में जनता विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने के लिए बंगलौर भेजा था। हेगड़े इतने कुशल राजनीतिज्ञ हैं कि तिकड़म लगा कर खुद ही मुख्यमंत्री बन बैठे। पार्टी पहली बार सत्ता में आयी थी और वह भी पूर्ण बहुमत में नहीं थी। कांग्रेस-इ विरोधी दूसरी पार्टियों के समर्थन से जनता पार्टी ने सरकार बनायी थी। पार्टी में प्रारंभ से ही दो जातियों का दबदबा रहा है और राज्य की राजनीति इन्हीं के इर्द-गिर्द चक्कर काटती रही है। ये जातियां हैं, वोक्कलिगा और लिंगायत। एचडी देवेगौड़ा वोक्कलिगा हैं और अपनी जाति में इनकी धाक है। लिंगायतों के दबाव के बावजूद हेगड़े ने देवेगौड़ा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। सिंचाई मंत्री के रूप में देवेगौड़ा पर बीसियों आरोप लगे और वह अखबारों की सुर्खियों में रहे। पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हेगड़े ने उन्हें मंत्री पद से हटाकर राज्य जनता पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, जहां देवेगौड़ा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गये। पार्टी की स्थिति मजबूत करने के बजाय उन्होंने राज्य भर में अपनी स्थिति में इजाफा किया। मजबूरन उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा।

हेगड़े के बाद देवेगौड़ा अपने आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे। इधर, एसआर बोम्मई गत वर्षों में हेगड़े के खास विश्वासपात्र बन गये, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर बैठने का ख्वाब बोम्मई भी देखने लगे। बीच-बीच में कई अवसरों पर हेगड़े ने इस आशय की सार्वजनिक घोषणाएं भी कीं कि वह अब मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाहते हैं। हेगड़े की इन घोषणाओं ने उनके विश्वास को बल प्रदान किया कि वह शीघ्र की मुख्यमंत्री बन सकेंगे। जैसे ही जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अजीत सिंह को बिठाने का निश्चय हुआ, वैसे ही कर्नाटक में जनता पार्टी प्रभावित हुई। हेगड़े, जो केंद्र की ओर मुखातिब थे, लौटकर अपने घर को आये और देवेगौड़ा की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री पद के लिए छटपटाते एचडी

साक्षात्कार/एमपी प्रकाश,

पार्टी पर आये संकट के जिम्मेदार देवेगौड़ा ही हैं

कर्नाटक के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा राज्य जनता पार्टी के अध्यक्ष एमपी प्रकाश इन दिनों पार्टी एकता के प्रयासों में पूरी तरह लगन से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेगड़े तथा असंतुष्टों के नेता एचडी देवेगौड़ा के बीच सुलह करवाने में मध्यस्थ का रोल अदा कर रहे हैं—एमपी प्रकाश। मजे की बात यह है कि देवेगौड़ा के अनुसार एमपी प्रकाश ही झगड़े की जड़ हैं, क्योंकि देवेगौड़ा ने हाल ही हुए विधान परिषद चुनावों में समझौते के लिए वार्ता की पहली शर्त रखी थी कि प्रकाश को पार्टी अध्यक्ष पद से मुक्त कर उनके स्थान पर सिद्दरामैया को बिठाया जाये। एमपी प्रकाश से हुई बातचीत के अंश:

माया: *राज्य जनता पार्टी में वर्तमान संकट क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं?*

प्रकाश : जब कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, तो इस प्रकार के संकट पैदा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुख्यमंत्री हेगड़े ने कई बार यह घोषणा की थी कि वह अब मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाहते हैं और उनकी जगह किसी अनुभवी और योग्य उम्मीदवार का चयन पार्टी को कर लेना चाहिए। उनकी इस घोषणा से पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा अपने आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझने लगे। काफी इंतजार के बाद भी उन्हें यह सुअवसर नहीं मिला, तो उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया। वर्तमान संकट का मूल कारण यही है। दूसरे शब्दों में हम इसे 'परसनालिटी क्लैश' भी कह सकते हैं।

माया : *अप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं?*

प्रकाश : यह तो दिखती बात है। एचडी देवेगौड़ा इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी का भला-बुरा समझते हैं। यदि किसी विषय को लेकर उनके मतभेद होते हैं, तो उसे पार्टी के अंदर निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सरेआम पार्टी की इज्जत मिटाने पर उतारू हो गये। उन्होंने इसके लिए 'मीडिया' का सहारा लिया। देवेगौड़ा जैसे नेता से यह आशा कैसे की जा सकती थी?

माया : *विधान परिषद चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार विद्याधर गुरुजी को अंतिम क्षणों में आपने चुनाव से अलग कर लिया। क्या आपको अंसतुष्ट उम्मीदवार के समक्ष उनकी हार निश्चित रूप से होने का पूर्वाभास हो गया था?*

देवेगौड़ा ने आखिर बागी बनने का फैसला कर लिया।

विरोध का लावा: राज्य जनता पार्टी में पहली बार खुलकर विरोध सामने आया, गत राज्यसभा के लिए हुए चुनावों में। पार्टी के अंदर-ही-अंदर बने दो धड़े वकील जेठमलानी की उम्मीदवारी को लेकर झगड़ पड़े। देवेगौड़ा धड़े ने रामजेठमलानी की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया। इस ग्रुप का कहना था कि 'बाहर' के एक व्यक्ति को क्या इसलिए राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाये कि वह मुख्यमंत्री के बेटे भरत हेगड़े का वकील है? उस समय मामला सुलझ सकता था, परंतु रामकृष्ण हेगड़े अपने निर्णय पर अड़े रहे। देवेगौड़ा के साथ सात मंत्रियों और ५० विधायकों ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बंबई से मधु दंडवते दौड़े-दौड़े आये और उन्होंने अंतिम क्षणों तक अपने प्रयासों के कारण असंतुष्टों को राजी कर लिया। फलस्वरूप, मतदान की समाप्ति के आधा घंटे पूर्व असंतुष्ट विधायकों ने अपने मतों का प्रयोग किया। मधु दंडवते ने यह आश्वासन दिया था कि असंतुष्टों की शिकायतों को सुना जायेगा और पार्टी हाईकमान इन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा।

अनेक बैठकों के बावजूद हेगड़े और देवेगौड़ा के मतभेदों को मिटाया नहीं जा सका। कहा तो यह भी जाता है कि जब संकट स्वयं पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पैदा किया हो, तो उसे मिटाना किसी के लिए उतना आसान कैसे हो सकता है? राज्यसभा चुनावों के बाद भी जब बागियों की बात नहीं सुनी गयी, तो वे विधान परिषद के चुनावों का इंतजार करने लगे। इन चुनावों में उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के समक्ष बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े कर दिये। नाम वापस लेने की तिथि निकल जाने के बाद भी तीन उम्मीदवार मैदान में डटे रहे।

बागियों की शर्त: देवेगौड़ा गुट ने हेगड़े के समक्ष यह शर्त रखी कि यदि राज्य जनता पार्टी अध्यक्ष एमपी प्रकाश के स्थान पर पूर्व मंत्री सिद्दरामैया को अध्यक्ष बना दिया जाये, तो अधिकृत उम्मीदवारों के समर्थन में बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटाये जा सकते हैं। हेगड़े ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। इसलिए तीन सीटों पर 'वफादारों' और 'बागियों' की लड़ायी में दो सीटों पर बागी उम्मीदवार विजयी हुए। इस विजय ने असंतुष्टों के हौसले बुलंद कर दिये हैं और वे मुख्यमंत्री से नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की नीति के तहत त्याग पत्र की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस-इ भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर त्याग पत्र मांग रही है।

विधान परिषद के चुनावों में उम्मीदवारों का चयन करने वाली समिति में देवेगौड़ा भी शामिल थे, परंतु उनका कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के पूर्व उनसे कोई राय नहीं ली गयी। पार्टी अध्यक्ष एमपी प्रकाश इसे सरासर झूठ बताते हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने के पूर्व देवेगौड़ा को आमंत्रित किया गया था, परंतु वह बैठक में जानबूझ कर नहीं आये। इधर देवेगौड़ा ने बाद में यह भी कह दिया था कि समझौते के लिए उनकी एकमात्र शर्त पार्टी अध्यक्ष सिद्दरामैया को बनाना ही नहीं है, बल्कि यह तो उनकी प्रमुख शर्त है। इसके साथ ही कुछ और मांगें भी सरकार को माननी होंगी। बहरहाल, असंतुष्टों की मांगें न मानने के कारण संकट की दरार और चौड़ी हो गयी।

राजनीतिक तबकों में एक नया फार्मूला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सूत्र को लागू करने के लिए वफादारों तथा असंतुष्टों, दोनों गुटों में उत्सुकता है। इस फार्मूले के अनुसार एचडी देवेगौड़ा अथवा उनके द्वारा सुझाये गये किसी भी सदस्य को राज्य जनता पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाये। यदि हेगड़े को हटाने की जरूरत पड़े, तो उसे भी स्वीकार कर दूसरे नेता का चुनाव किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्व मंत्री एसआर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने पर दोनों गुट सहमत हो सकते हैं। इस प्रकार विधानसभा भंग होने से बच सकती है। हालांकि हेगड़े ने १४ जून को पुनः स्पष्ट रूप से विधान-सभा को भंग करने की संभावना से इनकार किया है।

वर्तमान परिस्थितियों में अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपनी-अपनी चालें चल रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने उपमुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्त को हाल ही में देवेगौड़ा से मंत्रणा करने के लिए बंगलौर भेजा। इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, यह तो पता नहीं चला, परंतु इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझा

प्रकाश: जी हां! मैं सत्य को छुपाना नहीं चाहता। हमें पता चल गया था कि विद्याधर गुरुजी के बजाय बागी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, इसलिए अंतिम क्षणों में हमने उन्हें चुनावी दंगल से हटा लिया। वैसे बिलकुल अंतिम क्षणों में उन्हें चुनाव से अलग करना भी हमारी एक चाल थी।

माया: ***विधान परिषद के चुनावों में तीन स्थानों पर आपकी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के समक्ष बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिनमें से दो स्थानों पर उनकी विजय हुई। इससे क्या यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह विजय देवेगौड़ा की है?***

प्रकाश: कतई नहीं। देखिए, असंतुष्ट उम्मीदवारों का यह दावा खोखला है कि उनकी संख्या ५० से भी कहीं अधिक है। जहां तक चुनावों का सवाल है, इसमें कई 'फैक्टर्स' काम करते हैं। कुछ मत जातिगत आधार पर पड़ते हैं, जिनका असंतोष से कोई मतलब नहीं होता। बागियों को जो मत मिले हैं, उनमें संभवतः ३ कांग्रेस-इ से तथा २ मत भाकपा या माकपा सदस्यों के हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा भी चुनावों में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए असंतुष्टों की कथित विजय को वफादारों पर बागियों की विजय की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

माया: ***आपने उम्मीदवारों के चयन के समय देवेगौड़ा से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया?***

प्रकाश: देवेगौड़ा से उम्मीदवारों के चयन पर बात हुई थी, परंतु उस समय उन्होंने कोई मांग नहीं रखी। वह तो उम्मीदवार चयन समिति के सदस्य भी थे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के पूर्व भी उन्हें आमंत्रित किया गया था, परंतु वह नहीं आये। बाद में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से मुझे हटाकर सिद्दरामैया को अध्यक्ष बनाने की मांग रखी। उनकी यह शर्त भी हमें अखबारों से पता चली।

माया: ***आप पार्टी की एकता के लिए अध्यक्ष पद नहीं त्याग सकते थे?***

प्रकाश: मैं तो तैयार था, परंतु पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। सिद्दरामैया को अध्यक्ष बनाने के पीछे देवेगौड़ा की दलील यह थी कि वह पिछड़ी जाति के नेता को ही पार्टी अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो हमने बसवय्या का नाम सुझाया जो पार्टी में वरिष्ठ भी हैं और राजनीतिक रूप से परिपक्व भी। बसवय्या सेंट्रल सिल्क बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जिला और तालुका स्तर पर भी उन्होंने काफी नाम कमाया है, सिद्दरामैया को राजनीति में प्रवेश किये कुल १०-१२ वर्ष हुए हैं। बसवय्या का नाम देवेगौड़ा को नहीं भाया। यह तो जरूरी नहीं कि जो नाम देवेगौड़ा सुझाएं, उसे ही मान लिया जाये।

माया: ***असंतुष्ट बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि हेगड़े अपना बहुमत सिद्ध करें। क्या उनकी मांग मान ली जायेगी?***

प्रकाश: सदन में रोज प्रस्ताव रखे जाते हैं, विभिन्न मंत्रालय अपनी मांगें रखते हैं। जब तक ये सब पारित हो रहे हैं, हमें बहुमत सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है! बिना बहुमत के कोई भी मांग सदन में स्वीकृत कैसे हो सकती है?

माया: ***वर्तमान परिस्थितियों में क्या विधान सभा भंग की जाने की संभावना है?***

प्रकाश: नहीं।

माया: ***पार्टी में आये संकट को दूर करने के आपको कोई आसार नजर आते हैं?***

प्रकाश: आशा तो है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देवेगौड़ा भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी का भला-बुरा तो उन्हें ही समझना है।

—श्रीपा

जाता है कि जब से हेगड़े ने जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अजीत सिंह को स्वीकार किया है, तब से देवीलाल हेगड़े से नाराज हैं और उन्होंने बनारसीदास गुप्त को जो निर्देश दिया कि 'केवल देवेगौड़ा से ही भेंट करनी है' इस बात की पुष्टि करता है। कर्नाटक में राजनीतिक पर्यवेक्षक देवीलाल और देवेगौड़ा की इस निकटता को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। उनके अनुसार कर्नाटक में यदि नयी पार्टी या लोकदल-ब की स्थापना हो जाये, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। साथ ही, दूसरी विचारधारा वालों का मानना है कि देवेगौड़ा यदि नयी पार्टी बनाना भी चाहेंगे, तो जनता पार्टी के निशान और झंडे के नीचे दूसरी पार्टी ही बनायेंगे। वह लोकदल या कांग्रेस-इ में नहीं मिलेंगे।

कांग्रेस-इ की भूमिका : वर्तमान स्थिति में कांग्रेस-इ की भूमिका स्पष्ट दिखायी नहीं दे रही, परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस-इ का इस पचड़े से कोई सरोकार नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह पिछले दिनों बंगलौर क्या गुल खिलाने आये थे, यह अभी पता नहीं चल पाया है। परंतु कांग्रेस-इ के महासचिव जगन्नाथ पहाड़िया के इस वक्तव्य से इंका के इरादे स्पष्ट हो जाते हैं कि 'हेगड़े के खिलाफ होने वाली किसी भी क्रांति को हम पूरा समर्थन देंगे।' अपना नाम गुप्त रखने वाले एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने कहा कि 'हम दिल्ली से आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस-इ की भूमिका वही होगी, जो पार्टी हाईकमान चाहेगा।'

इधर मुख्यमंत्री, रामकृष्ण हेगड़े यह इतजार कर रहे हैं कि असंतुष्ट अगला कदम क्या उठाते हैं? उधर, असंतुष्ट भी इसी इंतजार में हैं कि मुख्यमंत्री उन पर क्या कार्यवाही करते हैं? देवेगौड़ा ने अपनी जनसभाओं में हेगड़े सरकार की खुली छीछालेदर करनी शुरू कर दी है। उनके स्वर में खुफिया जांच के बाद आये तथ्यों से भी फर्क नहीं पड़ा है, जिसमें उनके और उनके बेटे एचडी खन्ना पर लगे ४८ प्लाटों को बेनामी अलाट कराने का आरोप सही पाया गया है। ये आरोप मार्च में भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य बीबी शिवप्पा ने लगाये थे। देवेगौड़ा तो यहां तक कहते हैं कि मुझे राजनीतिक रूप से खतम करने का प्रयास हेगड़े के साथ-साथ जनता पार्टी को भी मिट्टी में मिला देगा। वह हेगड़े को मजबूर करना चाहते हैं कि हेगड़े उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

बहरहाल, जून में हुए चुनावों के परिणाम तथा असंतुष्टों की गतिविधियां इस बात के स्पष्ट संकेट देती हैं कि हेगड़े-देवेगौड़ा विवाद के कारण कर्नाटक में जनता पार्टी बारूद के ढेर पर बैठी है। इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पार्टी की छवि पर भी खराब असर पड़ रहा है। हालांकि, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं मानते। फिर भी, चुनाव के नतीजों को देखकर तथा पार्टी के आंतरिक कलह के कारण जुलाई में होने वाले विधान परिषदों के चुनावों पर पड़ने वाले इसदुष्प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता।

—श्रीकांत पाराशर

साक्षात्कार/एके **सुब्बैया,**
कांग्रेस-इ नेता

जनता सरकार के दिन अब गिनती के हैं

माया : ***राज्य में आज जो जनता सरकार की स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जनता सरकार का भविष्य आपको कैसा लग रहा है?***

सुब्बैया : जनता सरकार के दिन अब गिनती के रह गये हैं। इसका अब भविष्य कुछ भी नहीं है। जनता सरकार खुद अपनी मौत मरेगी। दरअसल, अब जनता पार्टी का ही अंत आ गया है। जयप्रकाश नारायण ने जिस पार्टी की स्थापना की थी, आज यह वह जनता पार्टी नहीं रह गयी है। आज इस पार्टी में भ्रष्ट, पद-लोलुप, स्वार्थी, मक्कार, धोखेबाज नेताओं की भरमार है। इस पार्टी के विनाश को कोई नहीं रोक सकता।

माया : ***राज्य जनता पार्टी में जो संकट पैदा हुआ, उसके लिए आप हेगड़े और देवेगौड़ा में से किसे दोषी मानते हैं और क्यों?***

सुब्बैया : संकट के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, परंतु अधिक दोषी रामकृष्ण हेगड़े ही हैं। दरअसल, १९८३ में रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था, परंतु हेगड़े ने बड़ी चतुराई व चालाकी से यह पद हथिया लिया जो नीति विरुद्ध था। हेगड़े का मुख्यमंत्री बनना लोकतंत्र पर जानलेवा हमले के समान था। मैंने इसलिए तत्काल इसका विरोध किया था और भाजपा द्वारा हेगड़े सरकार को समर्थन देने के पक्ष में नहीं था। फलस्वरूप, मुझे भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। उस समय किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु आज हेगड़े प्रशासन को देखकर सब को पता लग ही गया है कि मैं कितना सच था।

माया : ***असंतुष्ट उम्मीदवारों की विजय पर आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग की है। यदि हेगड़े इस्तीफा दे देते हैं और विधानसभा को भंग कर देते हैं, तो क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस-इ राज्य में अपनी सरकार बना सकेगी?***

सुब्बैया : निश्चित रूप से अगले चुनावों में हमारी विजय होगी। हालांकि हेगड़े विधानसभा भंग करेंगे, ऐसा नहीं लगता। कुछ भी हो, आगामी चुनावों में राज्य से जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जायेगा।

माया : ***यदि हेगड़े त्यागपत्र दे दें, तो क्या राज्यपाल एचडी देवेगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे?***

सुब्बैया : यदि जनता विधायक दल नये नेता का चुनाव करे और चाहे कि देवेगौड़ा उनका नेतृत्व करें, तो राज्यपाल निश्चित रूप से देवेगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ऐसी स्थिति में जनता सरकार गिरने से बच सकती है।

माया : ***पिछले विधान परिषद चुनावों में हेगड़े ने आपकी पराजय के लिए पूरा जोर लगा दिया था, ऐसा कहा जाता है। परंतु इस बार के चुनावों में हेगड़े आपके प्रति उतने गंभीर नहीं लगे। आपके प्रति उनके रवैये में इस परिवर्तन का आप क्या कारण मानते हैं?***

सुब्बैया : दरअसल, रामकृष्ण हेगड़े ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस-इ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूगा। हेगड़े ने सोच रखा था कि सुब्बैया के खड़े होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब उन्हें मेरी उम्मीदवारी का पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए चुप्पी साधने में ही उन्होंने भलाई समझी।

माया : ***सुब्बैयाजी, एक समय था जब आप कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। राज्य में कांग्रेस-इ की गुंडूराव सरकार को अपदस्थ कराने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। अब आप खुद कांग्रेस-इ में आ गये हैं। क्या यह समझा जाये कि अब कांग्रेस-इ की नीतियां बदल गयी हैं या फिर आपने अपनी नीतियां बदल कर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है?***

सुब्बैया : नहीं, नहीं। मैंने किसी भी पार्टी की नीतियों का कभी कोई विरोध नहीं किया। मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूं। मैं किसी भी भ्रष्ट सरकार का विरोध करने में कतई नहीं हिचकिचाता। पहले मेरी यही धारणा थी कि कांग्रेस-इ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी है, इसलिए मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा। परंतु जब जनता पार्टी सत्ता में आयी, तब मैंने देखा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है और यह पार्टी तो कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट है। कांग्रेस-इ में आने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि इस पार्टी में कितने 'क्लीन' लोग भी हैं, जबकि जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में आप एक भी नाम ऐसा नहीं पायेंगे, जो भ्रष्टाचार से परे हो। अटल बिहारी वाजपेयी भी भ्रष्ट हैं, स्वार्थी हैं, अवसरवादी हैं। जब तक मैं कांग्रेस से दूर रहा, तब तक इस यथार्थ को कैसे समझ सकता था?

—श्रीपा

छाया : मुश्ताक अहमद

WATERBURY'S

वाटरबरीज़ सुरक्षा

बरसात के मौसम में लोग सर्दी-खांसी के शिकार अक्सर हो जाते हैं. लेकिन जब वाटरबरीज़ आपके परिवार की सुरक्षा में तैनात हो, तो सर्दी-खांसी की एक न चले.

क्योंकि इसमें मिले हुए मिनरल और आयरन आपमें सर्दी से मुकाबले की ताकत खूब बढ़ाएं, और क्रिओसोट और गावाकॉल खांसी को दूर भगाएं.

यानी वाटरबरीज़ में है आपकी सुरक्षा का अचूक उपाय. याद रखिए आपका परिवार इससे वंचित न रह जाए.

Waterbury's Compound

वाटरबरीज़ रेड लेबल

सर्दी और खांसी के लिए आपके परिवार का विश्वसनीय रक्षक.

LINTAS WHL WRL P 1 2418 HI

अशोक सेन

अधर में

केन्द्रीय विधि मंत्री के पद का त्याग कर जनमोर्चा में शामिल हुए अशोक सेन का उनके गृहराज्य प० बंगाल में कैसा स्वागत हो रहा है?

लगभग पांच दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद, उसकी सदस्यता छोड़े बिना ही, जनमोर्चा में आ जुटे पूर्व केंद्रीय विधिमंत्री अशोक सेन अपने गृहराज्य पश्चिम बंगाल में आजकल दो नावों पर सवार आदमी के रूप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऊपर-ऊपर से वह न तो बहुत उत्साहित दिखायी देते हैं और न बहुत चिंतित। सामान्यत: ऐसा आदमी या तो बहुत चालाक होता है या निपट मूढ़। या तो वह दोनों विकल्प बनाये रखता है या कहीं का नहीं रह जाता। अशोक सेन को मूढ़ नहीं माना जा सकता। लेकिन राजनीति में वह इतने समर्थ भी नहीं हैं कि अधिक समय तक उनके लिए दोनों विकल्प बने रहें। कांग्रेस के भीतर तो स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ रोष उभर ही आया है, अपनी ढुलमुल बातों के कारण वह जनमोर्चा में भी विश्वसनीय नहीं बन पा रहे हैं।

अशोक सेन ने पिछली ७ मई को नयी दिल्ली स्थित वीपी सिंह के आवास पर जनमोर्चा में शामिल होने की घोषणा की थी। वहां वीपी सिंह के अलावा, अरुण नेहरू, आरिफ मुहम्मद खां और सतपाल मलिक भी थे। इस घोषणा के बाद सेन ने एक लंबा बयान भी दिया। उसमें पश्चिम बंगाल के नेतृत्व और राजीव गांधी की कड़ी आलोचना थी, राज्य के उद्योगों की दयनीय स्थिति का जिक्र था और सेन की अपनी सफायी थी, "मंत्री रहते समय मैंने पश्चिम बंगाल के बीमार उद्योगों को बचाने की भरसक चेष्टा की, लेकिन इस प्रयास में राजीव गांधी और केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली।" बयान में उनके जनमोर्चा में शामिल होने या कांग्रेस से हटने का जिक्र तक नहीं था। यह भी एक सच है कि मंत्री पद छोड़ते समय या उसके पहले सेन ने बंगाल के उद्योगों से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। यह बयान उन्होंने केवल बंगालियों का समर्थन पाने के लिए दिया था।

पश्चिम बंगाल में, खासकर कलकत्ता में जहां से वह अब तक चुनाव जीतकर संसद में जाते रहे हैं, अशोक सेन की नयी पैंतरेबाजी पर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। उसकी एक झलक २७ मई को कलकत्ता में जनमोर्चा के राज्य सम्मेलन के समय देखने को मिली। दिन के तीसरे पहर झंडों से सजे और खचाखच भरे महाजाति सदन में माकपा के वरिष्ठ मंत्री विनय चौधरी, भाकपा के सत्य भट्टाचार्य, फारवर्ड ब्लाक के नलिनी गुहा, पश्चिम बंगाल सोशलिस्ट पार्टी के विमान मित्र, जनता पार्टी के समर गुहा, जनमोर्चा के आरिफ मुहम्मद खां और विद्याचरण शुक्ल भी उपस्थित थे। सम्मेलन में अशोक सेन के आते ही विनय चौधरी ने बड़ी गरमजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सभागार में नारे गूंज उठे 'अशोक सेन जिंदाबाद, विनय चौधरी जिंदाबाद।' कई कार्यकर्ता मंच पर आ गये। एक ने अशोक सेन के सीने पर जनमोर्चा का बैज भी लगा दिया। शीघ्र ही उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। पहली बार अशोक बाबू के मुंह से केंद्र सरकार के विरोध में और विपक्ष के समर्थन में बातें निकलीं, "जो लोग दिल्ली की चाटुकारिता करेंगे, उनको पश्चिम बंगाल में एक भी वोट नहीं मिलेगा। राजीव गांधी के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, यदि मौत भी होती है, तो वह गौरव की बात होगी।" इसके साथ ही छात्र परिषद के युवकों ने सभागार में ही वीपी विरोधी तथा राजीव समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मियों और स्वयंसेवकों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया, तो महाजाति सदन के बाहर सभासद, शोभन चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में मजदूर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारी शोर-शराबे के साथ नारे लगाने लगे, "करोड़ों रुपए का मालिक, सीपीएम का दलाल अशोक सेन मुर्दाबाद... दलबदलू अशोक सेन संसद और इंका से इस्तीफा दें... विश्वासघाती अशोक सेन से फौरन इस्तीफा लिया जाये।" इस बीच अशोक सेन माइक के पास खामोश खड़े हास्यास्पद बने रहे। शोरगुल बंद होने पर फिर वह बोले, लेकिन उखड़े माहौल में उनकी बात सुनता कौन था?

इस्तीफे की मांग: इसके पहले भी सेन ने बंगाल पाटरीज फाटक पर मजदूरों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के साथ सौतेले सलूक के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी। वहां भी कांग्रेस नेताओं ने सेन को विश्वासघाती कहकर पार्टी से निकाले जाने की मांग की थी। उसी समय सेन यह भी समझ गये कि अब लोकसभा के लिए उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलना संभव नहीं है। उन्हें अब पार्टी से प्राय: बाहर ही माना जा रहा है। ऐसे में, वाकई वह एक सवाल बन गये हैं। क्या जनमोर्चा में उन्हें सम्मानप्रद स्थान मिल पायेगा? क्या वह वामपंथी मोर्चे में चले जायेंगे? या कांग्रेस में लौट जायेंगे? पश्चिम बंगाल के पिछले अनुभव बताते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता केंद्रीय नेतृत्व का विरोध कर सफल नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल की कांग्रेसी राजनीति में बरकत गनी चौधरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनमोर्चा में अशोक सेन के शामिल होने के बारे में उनकी राय है: "अशोक बाबू पार्टटाइम पोलिटिशियन हैं। ग्रास-रूट से उनका कोई मतलब नहीं है। हमेशा वह अपने को लेकर परेशान हैं। कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है, यह समझ कर ही वह जनमोर्चा में गये होंगे। अशोक सेन की कोई राजनीतिक छवि नहीं है कारण वह कांग्रेस के लिए कोई फैक्टर ही नहीं हैं। उनके जनमोर्चा में जाने से पश्चिम बंगाल कांग्रेस को रत्ती भर भी नुकसान न होगा। कांग्रेस की सदस्यता छोड़े बिना दूसरी पार्टी में जाना एक प्रकार का अवसरवादी क़दम है। उन्हें संसद की सदस्यता भी छोड़नी चाहिए।

अशोक सेन के संसदीय चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस संगठन में सबसे पहले जिनका नाम लिया जा सकता है, वह हैं प्रफुल्ल कांति घोष। अशोक सेन से विशेष घनिष्ठता के कारण प्रफुल्ल बाबू उन्हें 'भैया' कहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति की जानकारी रखनेवालों का कहना है कि प्रफुल्ल बाबू का संगठन ही अशोक सेन का राजनीतिक आधार है। अशोक सेन के जनमोर्चा में शामिल होने के बारे में उनका कहना है: "ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में 'भैया' कांग्रेस से विश्वासघात करेंगे। 'भैया' के इस काम से मुझे बड़ा कष्ट है। पर भैया ने अपने स्वार्थ से ही ज्योति बाबू से हाथ मिलाया है। उनके लिए वाममोर्चा सरकार की जरूरत तब तक है, जब तक वह अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति वापस नहीं पाते।"

विधि विशेषज्ञ के रूप में अशोक बाबू चाहे जितने बड़े हों, उनका राजनीतिक चरित्र शायद किसी से छिपा नहीं है। स्वतंत्रता से पहले राजनीति में उनकी भूमिका कोई महत्वपूर्ण नहीं थी, हालांकि वह कहते हैं कि नेताजी के आह्वान पर कांग्रेस में आये थे।

अशोक बाबू सक्रिय रूप से कभी राजनीति में नहीं आये। लगता है, राजनीति उनके लिए हमेशा गौण रही। राजनीतिक आधार बनाने के बदले

साक्षात्कार/
अशोक सेन

भविष्य की परवाह नहीं

माया: *एक बार आप कहते हैं कि जनमोर्चा में शामिल हो गये हैं, फिर यह भी कहते हैं कि कांग्रेस नहीं छोड़ी। क्या आपकी दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं?*

अशोक सेन: परस्पर विरोधी क्यों हैं? मैं तो अब भी कह रहा हूं कि जनमोर्चा में शामिल हुआ हूं। फिर यह भी कह रहा हूं कि कांग्रेस नहीं छोड़ी। कांग्रेस क्यों छोड़ूंगा? क्या नेताज़ी ने कांग्रेस छोड़ी थी? जब उन्होंने फारवर्ड ब्लाक बनाया था, तब भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। मैं तो उन्हीं का अनुयायी हूं।

माया: *फिर कांग्रेस छोड़ने का आपका कोई विचार नहीं है?*

सेन: शुरू से कांग्रेस में हूं, इसलिए अब कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।

माया: *आप कह रहे हैं कि शुरू से कांग्रेस में हैं, लेकिन १६७८ से १६८० तक आप जनता पार्टी में थे। है न?*

सेन: आप गलत कहते हैं।

माया: *दल-बदल विरोधी कानून के तहत क्या आपकी संसद की सदस्यता निरस्त होने की आशंका है?*

सेन: आशंका हो न हो, वह कोई बड़ी बात नहीं है। संसद की सदस्यता निरस्त करने-कराने के बारे में जिनको सोचना है, वही सोचा करें।

माया: *संसद की सदस्यता निरस्त करनेवाला कानून तो आपने ही कानून मंत्री रहते समय लागू किया था?*

सेन: शायद किया था। अब उस बात को याद रखने की जरूरत नहीं समझता।

माया: *यदि इस समय आपकी संसद की सदस्यता निरस्त हो जाये, तो क्या करेंगे?*

सेन: यह तो अभी से बताना संभव नहीं है। यदि वैसा हो जाये, तो तब तय करूंगा कि क्या किया जायेगा।

माया: *बहुतों को यह उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर आप जनमोर्चा में चले जायेंगे। ऐसा अप्रत्याशित निर्णय लेने के पीछे कौन-सा बड़ा कारण हो सकता है?*

सेन: इसका सीधा-सा जवाब यही है कि कांग्रेस नेतृत्व मुझे खुश नहीं कर सका। मैंने जो कुछ कहना चाहा, जिन योजनाओं और परियोजनाओं की तरफ पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया, वह सब उपेक्षित रह गया। इसीलिए जनमोर्चा में जाने की बात सोची और गया भी। इसलिए जनमोर्चा से लाभ या हानि होने का सवाल नहीं उठता।

माया: *लाभ-हानि से मेरा मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन नहीं है। जनमोर्चा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?*

सेन: जनमोर्चा आंदोलन कांग्रेस का शुद्धीकरण आंदोलन है।

माया: *कांग्रेस में रहकर क्या वैसा करना संभव नहीं था?*

सेन: घुमा-फिराकर फिर वही बात आयी है। मैंने तो कह दिया कि कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन पार्टी से थोड़ा हटकर किया गया आंदोलन जितना कारगर होता है, उतना पार्टी के अंदर रहकर नहीं होता। मैंने पश्चिम बंगाल की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया, जैसे वक्रेश्वर लघु विद्युत केंद्र की समस्या या हलदिया के पेट्रोकेमिकल्स की। लेकिन केंद्र ने उनके प्रति ऐसी उदासीनता दिखायी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इसीलिए जनमोर्चा में आया हूं। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का शुद्धीकरण आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल है।

प्रस्तुति: गुरुप्रसाद महांति

उन्होंने अपने कानूनी व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया। संगठन की क्षमता उनमें कभी नहीं आयी। फिर वह राजनीतिक क्षेत्र में कैसे इतने आगे आये? इसमें डा० विधानचंद्र राय और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान-रहा।

इसलिए अशोक बाबू अगर इस समय राजनीतिक क्षेत्र में अपने को दिशाहीन नहीं समझ रहे, तो भविष्य में जरूर समझेंगे, क्योंकि जनमोर्चा में जाने के बाद भी वह कभी कह रहे हैं, "मैं तो कांग्रेस में ही हूं" तो कभी "जनमोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है।" इसका मतलब है कि वह किसी भी पार्टी के प्रति पूरी आस्था व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का विश्वास खो दिया, तो किसी विपक्षी पार्टी के लिए भी वह विश्वसनीय नहीं बन सकेंगे। संभवतः इलाहाबाद की लोकसभाई सीट के उपचुनाव को ध्यान में रखकर वीपी सिंह ने उनके दोमुंही बयानों पर ध्यान नहीं दिया और उनका स्वागत किया। सेन ने वीपी के चुनाव-प्रचार में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद का दौरा भी किया था। लेकिन लगता है कि अशोक सेन अच्छी तरह सोच-समझकर कांग्रेस से अलग हुए बिना जनमोर्चा में गये हैं। जब तक वह किसी एक पार्टी का विश्वास प्राप्त नहीं करते, तब तक दो नावों पर पांव रखकर चलना उनकी मजबूरी है।

—रमाप्रसाद घोषाल और अमित विक्रम राणा

चुटकी की चुटकियां
ज़िन्दगी की भोली-भाली मस्तियां
अब नये सजधज के साथ नये आकर्षक पॉउच पैक में !
Chutki
Chutki
प्यार का मस्ती भरा एहसास
चुटकी पान मसाला!

चुटकी पान मसाला प्यार के रिश्तों में एक अनोखी ताज़गी और मीठी-मीठी महक लाता है। हर मौके, हर महफ़िल में रंग जमाता है। सौंफ़, छुआरा और इलायची वाला चुटकी पान मसाला कितना है निराला !

कितनी टिकाऊ है पवार की हंसी ?

यद्यपि महाराष्ट्र १६ जून के उपचुनावों के दायरे में नहीं था, फिर भी इंका को निराश करने वाले उपचुनावों के ठीक बाद एसबी चह्वाण को हटाकर शरद पवार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसी क्या गरज पड़ गयी इंका आलाकमान को ? पवार से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं ? और पवार की संभावनाएं क्या हैं ?

हाल ही हुए संसद और विधानसभा उपचुनावों के बाद जिन दो राज्यों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, उनमें से एक महाराष्ट्र भी है। यहां पर शरद पवार को शंकर राव चह्वाण की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया है। पवार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले वह प्रगतिशील प्रजातांत्रिक मोर्चे की सरकार में १८ जुलाई, १९७८ को मुख्यमंत्री बने थे और १७ फरवरी, १९८० तक बने रहे। बाद में उनकी सरकार को बरखास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था जो महाराष्ट्र के अब तक के इतिहास में ऐसी पहली घटना है।

चह्वाण को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग उनके पद संभालने के एक साल बाद ही शुरू हो गयी थी। वह १४ मार्च, १९८६ को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 'चह्वाण हटाओ' अभियान इधर पिछले २-३ महीनों में और तेज हो गया था। इस अभियान की कमान वैसे तो महाराष्ट्र राजनीति के दिग्गज वसंत दादा पाटील संभाले थे, परंतु इस मुहिम के अन्य कर्णधारों में वर्तमान मुख्यमंत्री शरद पवार भी एक थे। दो महीने पहले वसंत दादा पाटील, शरद पवार तथा रामाराव आदिक ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया था जो 'चह्वाण हटाओ' मुहिम से संबंधित था। इस ज्ञापन पर करीब १५० विधायकों के हस्ताक्षर थे। ज्ञापन को दादा पाटील ने प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दिया था। इस ज्ञापन के बाद प्रदेश के हरिजन और आदिवासी विधायकों ने भी इसी मकसद से दिल्ली का दौरा किया था। चह्वाण को दो साल पहले दादा पाटील के विरोध के बावजूद आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। उनके जिम्मे कुछ काम दिये गये थे जिनमें दादा-पवार की ताकत पर अंकुश लगाना, शिवसेना के बढ़ते प्रभाव को रोकना तथा भ्रष्टाचार के कारण खराब होती कांग्रेस की छवि निखारना आदि था। मुख्यमंत्री बनते ही चह्वाण ने गन्ना लाबी के, जिसके हितों का रक्षक दादा-पवार गुट है, खिलाफ कमर कस ली। लेकिन वह शिवसेना के बढ़ते प्रभाव को न रोक सके।

आठ साल बाद फिर : शपथ लेते शरद पवार

पिछले साल शिवसेना ने बंबई की विलेपार्ले सीट जीती थी। फिर उसने अपने पांव बंबई से बाहर पसारने शुरू किये थे। पूना तो क्या, उसका प्रभाव औरंगाबाद में उस समय स्पष्ट हो गया जब उसने वहां के कार्पोरेशन का चुनाव 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं' का नारा देकर लड़ा और २७ सीटें जीत लीं। शिवसेना के पार्षदों की इतनी बड़ी संख्या में विजय को आलाकमान ने गंभीरता से लिया। उसे महाराष्ट्र में कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा। फिर असंतुष्टों तथा विपक्ष ने चह्वाण को दंगे रोकने में विफलता के कारण आड़े हाथों लिया। असंतुष्ट और शिवसेना दोनों ही चह्वाण के लिए सिरदर्द बन गये थे।

चंद्रिका केनिया-विवाद : इधर यह सब चल रहा था, उधर उनके मंत्रिमंडल की सदस्या शिक्षा राज्य मंत्री चंद्रिका केनिया और बंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुरली देवड़ा के विवाद ने उनके सामने एक नयी समस्या खड़ी कर दी। मुरली देवड़ा के दादा पवार गुट से अच्छे संबंध हैं। इन सारे लोगों ने चंद्रिका केनिया के मामले की आड़ लेकर 'चह्वाण हटाओ' मुहिम और तेज कर दी। परंतु चह्वाण की प्रधानमंत्री तक सीधे पहुंच होने के कारण ये लोग खुले तौर पर उनको हटाने की बात करने से घबराते थे। आलाकमान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन में उसकी कोई रुचि नहीं है।

इसके थोड़े ही दिन बाद असंतुष्टों और चह्वाण, के भाग्य से जून '८८ के उपचुनावों में कांग्रेस बुरी तरह पिट गयी। आलाकमान ने १९९० के आम चुनावों के लिए इन परिणामों को कांग्रेस के लिए एक अशुभ संकेत माना। ऐसे नाजुक समय पर जार्ज की मेहरबानी से मुरली देवड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने में सफल हो गया। मुलाकात करने वालों में चह्वाण मंत्रिमंडल के दो सदस्य भी थे—डा० वैद्यनाथन सुब्रह्मण्यम और विलास सावंत।

मुलाकात के समय जब प्रधानमंत्री ने इनसे महाराष्ट्र की राजनीति का हाल पूछना चाहा, तो बात का रुख मोड़ने के अनिच्छुक नेताओं ने देवड़ा के दबाव के कारण सिर्फ इतना कहा, "सर, हम लोग सिर्फ केनिया के बारे में बात करने आये हैं।" देवड़ा सीधे चह्वाण को हटाने की बात कहने से डर रहे थे। असंतुष्टों के अभियान में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभा राव भी साथ दे रही थीं।

अंततः इन सब कारणों ने गुल खिलाया और अचानक शरद पवार २२ जून को दिल्ली बुलाये गये। फिर २३ जून की शाम को मुख्यमंत्री चह्वाण और प्रदेश इंका अध्यक्ष प्रभा राव को भी दिल्ली बुलाया गया। नेतृत्व-परिवर्तन के लिए व्यक्ति के चुनाव की बात आयी। चह्वाण चाहते थे कि विलास राव देशमुख या गन्ना लाबी में उनके खास समर्थक सांसद बालासाहब विरवे पाटील को मुख्यमंत्री बनाया जाये। दूसरे गुट की ओर से शरद पवार, शिवाजी राव निलंगेकर तथा रामाराव आदिक दावेदार थे। ये सभी मराठा हैं। अंत में मुख्यमंत्री का ताज शरद पवार के सिर पर रख दिया गया।

चह्वाण को इस तरह जल्दी हटाये जाने के पीछे एक दूसरा मत भी है। वह यह कि स्वयं चह्वाण दिल्ली आते वक्त यह नहीं जानते थे कि आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन पर विचार के लिए उन्हें बुलाया है। इसकी पुष्टि बाद में उन्होंने स्वयं की। इस मत को मानने वाले लोगों का कहना है कि आलाकमान की नाफरमानी ही चह्वाण को इस तरह ले डूबी। उनको कुछ ही दिन पहले दिल्ली से चंद्रिका केनिया, श्रीकांत जिचकार आदि कुछ अन्य मंत्रियों को हटाने का निर्देश दिया गया था, परंतु उन्होंने इस निर्देश की अनदेखी कर दी। फलस्वरूप उन्हें इस तरह आकस्मिक रूप से शरद पवार के लिए गद्दी खाली करनी पड़ी।

२० साल की कम उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले तथा ३६ साल की उम्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले शरद पवार अपनी गतिशीलता और साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। यह दूसरी बात है कि वह प्रदेश के सबसे धनी नेताओं में से एक हैं। साकाल भूमि घोटाले से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पवार उद्योगपतियों और भवन निर्माताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। अफसरशाही से भी उनके अच्छें संबंध हैं। वह काम करने और करवाने में यकीन रखते हैं।

राजनीतिक कौशल: फिलहाल, मुख्यमंत्री पवार ने ३६ सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है जिसमें २६ कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें १४ नये चेहरे हैं। मुख्यमंत्री पवार की राजनीतिक कुशलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन के समय उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हरिजनों, महिलाओं, पारसियों, मुस्लिमों, गुजरातियों और आदिवासियों सहित सभी को प्रतिनिधित्व मिले। पिछले मंत्रिमंडल के १६ मंत्रियों में सिर्फ काबीना स्तर के सुशील कुमार शिंदे तथा विलास राव देशमुख एवं राज्यमंत्री स्तर के तीन मंत्रियों को वर्तमान मंत्रिमंडल में लिया गया है। चर्चित परंतु विवादास्पद शिक्षा राज्यमंत्री केनिया को शामिल नहीं किया गया।

मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित वार्ता करने दिल्ली आये मुख्यमंत्री पवार से जब पत्रकारों ने शिवसेना के बारे में पूछा, तो उनका जवाब था, "शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी या पूरा विपक्ष, उनकी चुनौती राजनीतिक है।" उन्होंने इन सबको राजनीतिक धरातल पर ही पिछाड़ देने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी दल ने गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया, तो उनकी सरकार उससे सख्ती के साथ निबटेगी। उनका इशारा शिवसेना की तरफ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीत का असर महाराष्ट्र पर उन्होंने नकार दिया, परंतु जब एक पत्रकार ने कहा कि 'इलाहाबाद के नतीजे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया', तो पवार सहित दूसरों ने इस पर जोरदार ठहाका लगाया।

शरद पवार की यह हंसी अगले १८ महीनों तक बरकरार रहेगी या नहीं, कहना मुश्किल है, परंतु इतना अवश्य है कि दत्ता सामंत के निमंत्रण पर बंबई पहुंचे विश्वनाथ प्रताप सिंह का भारी स्वागत विपक्ष के हौसले मजबूत करेगा। दूसरी तरफ, मराठा और हिंदू भावनाओं को उभाड़कर सारे महाराष्ट्र में कैंसर जैसी फैलती हुई शिवसेना को सीमित रख पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और शायद यही शरद पवार के नेतृत्व की गतिशीलता की परख होगी कि वह शिवसेना और विंपक्ष को शिकस्त दे पाते हैं या नहीं तथा 'कजली कांग्रेस' को कितनी उजली बना पाते हैं। आखिर इन्हीं सबके लिए तो उन्हें ताज पहनाकर बंबई भेजा गया है!

बंबई ब्यूरो

शरद पवार की यह हंसी अगले १८ महीनों तक बरकरार रहेगी या नहीं, कहना मुश्किल है, परंतु इतना अवश्य है कि दत्ता सामंत के निमंत्रण पर बंबई पहुंचे विश्वनाथ प्रताप सिंह का भारी स्वागत विपक्ष के हौसले मजबूत करेगा। दूसरी तरफ, मराठा और हिंदू भावनाओं को उभाड़कर सारे महाराष्ट्र में कैंसर जैसी फैलती हुई शिवसेना को सीमित रख पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और शायद यही शरद पवार के नेतृत्व की गतिशीलता की परख होगी कि वह शिवसेना और विपक्ष को शिकस्त दे पाते हैं या नहीं तथा 'कजली कांग्रेस' को कितनी उजली बना पाते हैं।

Now, the city of ganges has a five star surprise for you.

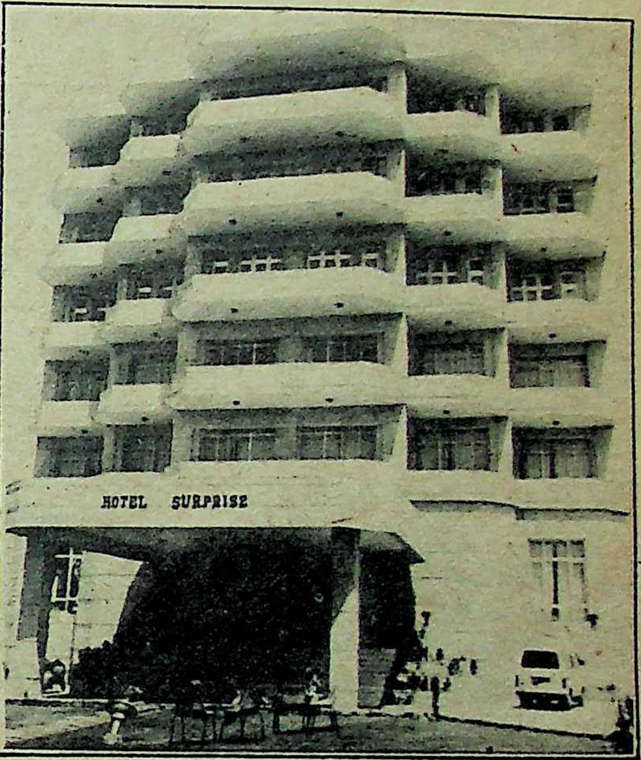

- ★ Centrally located-very close to Hardwar bus-stop and railway station
- ★ Airconditioned, wall-to-wall carpetted rooms with piped in channel music, colour TV & telephone. Luxury bathrooms.
- ★ Tastefully decorated Gazal restaurant for Chinese, Continental & Mughlai Cuisine.
- ★ Barbeque for outdoor parties.
- ★ Shopping arcade, swimming pool, beauty saloon & florist.

HOTEL
Surprise
HARDWAR

Hardwar-Delhi Road Jwalapur, Hardwar-249407
Tel.: 1522, 1146, 1148 Gram: 'Surprise'

Instant Reservation-Delhi Tel.: 697754

adEnvoys.

चुनाव का इंतजार

क्या तमिलनाडु में चुनाव सन्निकट हैं? चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की क्या रणनीतियां हैं?

पिछले चालीस वर्षों के अपने ऐतिहासिक अनुभव में तमिलनाडु इन दिनों राजनीति का चौथा स्वाद ले रहा है। पहला जायका राजाजी, कामराज और भक्तवत्सलम के कांग्रेस काल का था। आजादी के प्रथम बीस वर्षों का यह अनुभव प्रायः एकरस और ऊबाऊ था। लेकिन अमन और देश में प्रदेश की छवि की दृष्टि से बुरा नहीं था। दूसरा स्वाद द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (द्रमुक) के दस वर्षों ने दिया। विवादजनक राजनीति और संकरे नजरिए के कारण यह स्वाद आम तमिल के गले उतरना कठिन था। कुछ तो कांग्रेस ने 'हाथ से निकला राज' फिर से पाने के लिए अपने प्रचार से इसे बेहद कड़वा बना दिया था। तीसरी बार जायका बदला १९७६ में। एम करुणानिधि की द्रमुक सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकालीन अधिकारों के तहत बरखास्त कियें जाने और एमजी रामचंद्रन की अन्नाद्रमुक सरकार आने के साथ। जबान में चटखार पैदा कर तन-मन को तरोताजा रखनेवाला यह जायका तमिल जनता, खासकर नयी पीढ़ी के युवक-युवतियों को बहुत रास आया। यही सबब था अभिनेता से नेता बने रामचंद्रन के, देखते-देखते, समूचे तमिलनाडु पर 'युगनायक' बनकर छा जाने का। और अब चौथे जायके का दौर है। यह '८७ और '८८ के संधिकाल वाली उस 'शून्य' (वैक्यूम) की स्थिति से पैदा हुआ जब 'डेमी गाड' (देव पुरुष) अपनी वसीयत अनलिखी छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था, एक बवंडर चल पड़ा था उत्तराधिकार के लिए और उस बवंडर में दो औरतें और उनकी राजनीतिक सेनाएं आपस में गुत्थमगुत्था कर रही थीं। इनमें एक थी देवपुरुष की धर्मपत्नी और दूसरी कर्म क्षेत्र की सहयात्री। सहानुभूति की बदौलत उत्तराधिकार धर्मपत्नी को मिल गया। जानकी रामचंद्रन मुख्यमंत्री बन गयीं। लेकिन वह सत्ता संभाल नहीं पायीं। राजनीति धर्म नहीं मानती। वह कर्म मानती है, उसी की होती है। लिहाजा सारा लोकमत कर्म की साथी (देवपुरुष की प्रेयसी) जयललिता जयराम की तरफ हो गया। फोर्ट सेंट जार्ज का हंगामा सड़क पर निकल आया। खूब तमाशा हुआ। और एक महीने के अंदर ही ३० जनवरी, १९८८ को राजीव गांधी ने जानकी रामचंद्रन की सरकार बरखास्त कर दी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

दोहरा संघर्ष : जयललिता

तमिलनाडु में आज भी माहौल वही है। अर्थात लोकमत जयललिता के साथ है। सब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन खतम होना है। चुनाव होना-ही-होना है। इसकी घोषणा कभी भी अचानक हो सकती है। इसलिए सजग और तैयार रहना है, ताकि एमजीआर (रामचंद्रन) के दशक जैसा जायका फिर से मिल सके। इसी से तमिलनाडु चुनाव की प्रतीक्षा में है। शुरू में उसे बताया गया था कि चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे। उसने हिसाब लगाकर नतीजा निकाला कि २९ जुलाई के पहले चुनाव होंगे। लेकिन अब कोई कहता है कि यह चुनाव सितंबर में होगा और कोई कहता है कि जनवरी में होगा। यानी तब होगा, जब राजीव कांग्रेस को यकीन हो जाये कि उसे बहुमत मिल जायेगा।

हर दल दलदल में : खैर, इससे साफ है कि यह 'वैक्यूम' और बवंडर का स्वाद है और इसे लंबे समय तक नहीं रहना है। भले मुगालता ही कहा जाये, पर पांव जमाने का इतना बढ़िया मौका कोई राजनीतिक दल खोना नहीं चाहता। सारी राजनीति चार खेमों में बंट गयी है (१) अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक (एआईएडीएमके) का जयललिता खेमा जो इन दिनों गहरे संकट से गुजर रहा है। (२) जानकी रामचंद्रन गुट जो लगभग बेदम हो चुका है। (३) एम करुणानिधि का द्रमुक जिसके साथ भाकपा-माकपा भी हैं, और (४) कांग्रेस-इ जो खोया राज पाने के लिए सारे तरीके अपना रही है फिर भी तमिल विश्वास का भाजन नहीं बन पा रही है। इधर एक पांचवीं पार्टी भी चुनाव को ध्यान में रखकर अपने को सक्रिय करने में लगी है। यह है फिल्म अभिनेता शिवाजी गणेशन की पार्टी 'तामीजग मुन्नेत्र मुन्नानी' जो श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर अपने हक में हवा बना रही है। पिछली जनवरी में जानकी रामचंद्रन की सरकार भंग कर दी जाने के विरोध में गणेशन ने कांग्रेस-इ छोड़कर यह पार्टी बनायी थी।

चुनाव का बुखार : तमिलनाडु इधर चुनाव का बेकरारी से इंतजार कर रहा था। राजधानी (मद्रास) तो मानो चुनाव के ज्वर से बदहवास थी। राजनीतिक दल बाहर और भीतर दोनों तरफ से हरकत में थे। अंदर-अंदर मोर्चाबंदी और जोड़तोड़ घनघोर रूप से चल रही थी, तो बाहर-बाहर हर राजनीतिक दल समर्थन और विरोध प्रदर्शित कर माहौल का रुख अपनी ओर मोड़ने में लगा था। पूरे शहर की दीवारों पर चुनावी इबारतें थीं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर रंग-बिरंगे पोस्टर थे। सभी चौराहों पर आदमकद या इससे भी बड़ी आकर्षक तस्वीरें थीं। एमजीआर और जयललिता की युगल जोड़ी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जीके मूपनार, करुणानिधि, सबकी चुनावी झांकी मिल जाती थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्ति (२९ जुलाई) के पहले होने के आसार नहीं दिखाई देने से प्रायद्वीपीय भारत का यह राज्य अब कुछ ठंडा पड़ता जा रहा है। पूरे तमिलनाडु पर राष्ट्रपति शासन के दूसरे दौर का साया मंडरा रहा है जो राज्य के लोगों को कतई नापसंद है।

दरअसल तमिल जनता के मनमोहन एमजी रामचंद्रन के निधन से बनी रिक्तता ने जो बवंडर उठाया, उसका पहला शिकार उनकी पार्टी अन्नाद्रमुक ही हुई। वह दो विरोधी खेमों में बंट गयी। एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और प्रेयसी जयललिता जयराम के खेमों की आपसी उठापटक के ही तहत पिछली जनवरी में वह राजनीतिक तमाशा हुआ जिसमें विधायकों ने सदन के अध्यक्ष पीएच पंडियन के साथ बदसलूकी की और अध्यक्ष ने २७ विधायकों को निलंबित कर दिया। केंद्र मानो ऐसे ही हंगामे की ताक में था। राज्यपाल अलक्जेंडर ने रिपोर्ट दी। बस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

जल्दी चुनाव के लिए सबसे अधिक छान-पगहा तुड़ाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, उनकी पार्टी द्रमुक और उनकी सहयोगी पार्टियां सीपीआई और सीपीएम। इस समय की हवा उन्हीं के अनुकूल है। पालिका-

पंचायत चुनावों में द्रमुक ने अपनी स्थिति भी मजबूत कर ली है। कांग्रेस-इ तथा जयललिता गुट दोनों इन्हें समान रूप से अपने शत्रु मानते हैं। इसलिए चुनाव के बारे में आंदोलन-प्रदर्शन कर रहे करुणानिधि और उनके समर्थकों की बात नहीं सुनी जायेगी।

इंका का पैंतरा: तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही कांग्रेस-इ राज्य में अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाने में लग गयी थी। अप्रैल-मई में राजनीतिक गतिविधियां एकबारगी तेज हो गयीं। नयी दिल्ली के बड़े-बड़े अधिराज मद्रास पहुंचे। उन्होंने एमजी रामचंद्रन के मायूस और नादान समर्थकों को ढाढ़स बंधाया कि उनके लिए अब भी उम्मीदें हैं। एमजीआर के निधन पर गहरी संवेदना जताते हुए राजीव गांधी के प्रतिनिधियों ने तमिलों के दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की कि उनके हितों की रक्षा अब एमजीजार के उत्तराधिकारी बनकर कांग्रेस-इ के लोग करेंगे। हकीकत यह कि रामचंद्रन-रहित तमिलनाडु राजनीतिक पैकारों के लिए सुखद संभावनाओं का बाजार बन गया है। हर पैकार, चाहे वह मर्द हो या औरत, अपने आपको एमजीआर की छवि के साथ पेश करने के लिए हाथ-पांव मारता रहा है।

एक खुला सच यह है कि दक्षिण भारत के चार राज्यों में से सिर्फ तमिलनाडु को ही पाने की आशा कांग्रेस-इ फिलवक्त कर सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही एक लंबे अरसे बाद गत मई में कांग्रेस-इ का तमिलनाडु अधिवेशन हुआ। इसके साथ ही इस गढ़ पर कब्जे के लिए पार्टी का चौतरफा अभियान चालू हो गया। असली कद से भी बड़े-बड़े इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और एमजीआर के चित्र मद्रास की आलीशान इमारतों की दीवारों और चौराहों पर मुसकराते हुए लोगों को इंका के समर्थन का इशारा देने लगे। अधिवेशन समाप्त होते ही राज्यपाल और राजीव गांधी के परम विश्वासपात्र पीसी अलक्जेंडर ने राज्य में तेजी से उद्योगीकरण, जलपूर्ति, रोजगार आदि के कार्यक्रम चालू कर दिये। तमिल जनता को यह भी बताया गया कि इस तरह की कई योजनाएं दिल्ली की फाइलों में हैं जो विधानसभा चुनावों की घोषणा के ठीक पहले तमिलनाडु की जनता के सामने लायी जायेंगी। कांग्रेस-इ की ओर से ऐसे आश्वासन अब भी दिये जा रहे हैं। अभी २०-२१ जून को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने ऐसे आश्वासनों को दुहराया और अपने भाषण में मुख्य रूप से तीन बातें रखीं: (१) यदि लोग फिर कांग्रेस-इ का भरोसा करें, तो वह तमिलनाडु को एक ऐसी स्वच्छ तथा सक्षम सरकार देगी जो राज्य में कामराज, राजाजी और भक्तवत्सलम के शासन काल जैसी आर्थिक समृद्धि और अमन-चैन कायम करेगी। (२) आजादी के बाद, पहले २० वर्षों में कांग्रेस शासन में तमिलनाडु विकास और समृद्धि के रास्ते आगे बढ़ा, लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब से राज्य की आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक हालत दिनोदिन बदतर होती गयी है। (३) कुछ शक्तियां तमिलनाडु को विभाजित करने का कुचक्र चला रही हैं। इसी तरह कुछ ताकतें देश को भी बांटने की षड्यंत्र कर रही हैं। इसलिए एकता समय की सबसे बड़ी मांग है और एकता बनाये रखने में एकमात्र कांग्रेस ही समर्थ है।

तमिलों की पसंद: देश के दूसरे राज्यों से भिन्न तमिलनाडु का मुख्यमंत्री सिर्फ शासक दल का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक जंतु नहीं, बल्कि देवपुरुष होता है। उसके चित्र बड़े-बड़े कस्बों और छोटी-छोटी दुकानों में पूजे जाते हैं। ये चित्र करुणानिधि के हो सकते हैं, जयललिता के हो सकते हैं। लेकिन क्या मूपनार के भी हो सकते हैं? यह प्रश्न बेतुका ही नहीं, हास्यास्पद भी है। राज्य के मुख्यालय फोर्ट सेंट जार्ज के लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त (और सर्वाधिक संभावनावाली) उम्मीदवार तमिल फिल्मों और राजनीति की परी जयललिता ही हैं। वह ग्लैमर वाली महिला हैं, एक झांकी के लिए दूर-दूर से लाखों लोगों को खींचनेवाली सुंदरी हैं। पुराने त्रिकोण की यह दूसरी महिला ही तमिलों की निगाह में एमजीआर की राजनीतिक उत्तराधिकारी है। जयललिता अपने प्रेमी की जागीर पर अधिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वह द्रविड़ों के समूचे चावल-बेल्ट में अपना दावा प्रचारित कर रही हैं। वह लाखों की भीड़ जुटाना ही नहीं जानतीं, बल्कि भीड़ को कीमती वोटों में तब्दील करने का जादू भी जानती हैं। अब तक सबसे दमदार दिखायी देती रहीं जयललिता भी अपने गुट के साथ दोहरे संघर्ष से गुजर रही हैं। एक तरफ भंग विधानसभा के अध्यक्ष तथा जानकी समर्थक पीएच पंडियन (जिन्हें जयललिता समर्थक विधायकों से अपमानित होना पड़ा था) उनके चरित्र की बखिया उधेड़ रहे हैं, सीधे वेश्या कह रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री न बनने देने का अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी को आंतरिक कलह ने बिखराव के कगार तक पहुंचा दिया है।

जयललिता अपने प्रेमी की जागीर पर अधिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वह द्रविड़ों के समूचे चावल-बेल्ट में अपना दावा प्रचारित कर रही हैं। वह लाखों की भीड़ जुटाना ही नहीं जानतीं, बल्कि भीड़ को कीमती वोटों में तब्दील करने का जादू भी जानती हैं।

अन्नाद्रमुक का संकट: राज्य में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति का समय जैसे-जैसे करीब आता गया, चुनाव के लिए दलों की धमाचौकड़ी और जोड़तोड़ बढ़ी, वैसे-वैसे ही जयललिता गुट का संकट गहराता गया। एक अरसे से जारी गुट के नेताओं का आपसी मनमुटाव गुट के भविष्य पर धुंध बनकर छा गया है। संगठन, उसके कार्यकलाप और कांग्रेस-इ के साथ चुनावी गठजोड़ पर विचार के लिए २५ जून को मद्रास में आयोजित गुट के जिलासचिवों की बैठक में यह अंतर्विरोध सामने आ गया। जहां पनरुति एस रामचंद्रन और एस तिरुनवुकरासु विधानसभा की आधी-आधी सीटों की शर्त पर कांग्रेस के साथ समझौता कर लेने के पक्ष में थे, वहीं जयललिता सहित गुट का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर अड़ा था कि समझौता दो शर्तों पर हो—(१) २३४ सीटों में दो तिहाई पर जयललिता गुट चुनाव लड़े, शेष ७८ सीटों पर इंका लड़े और (२) कांग्रेस-इ जयललिता को भावी मुख्यमंत्री मानकर चुनाव लड़े। हाल के उपचुनावों के, खासकर इलाहाबाद के नतीजों ने जयललिता की पार्टी में इंका विरोधी विचारों को मजबूत किया है। लेकिन वह इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि द्रमुक ने वोट विभाजित कर चुनाव जीतने की अपनी मशीनरी दुरुस्त कर ली है। इसलिए इंका से समझौते के अभाव में गुट का चुनाव अभियान सिर्फ द्रमुक का मददगार बनकर रह जायेगा। बहरहाल, बैठक में जयललिता को राजीव गांधी से मिलकर गठजोड़ की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया गया। वीआर नेदुनचेझियन, एस तिरुनवुकरासु और पी कोलंदाइवेलु जैसें पार्टी की राजनीतिक समिति के सदस्यों और पूर्व मंत्रियों ने बैठक में शामिल न होकर अपना मनमुटाव जाहिर कर दिया।

अगले दिन इन्हीं मुद्दों पर पार्टी की राजनीतिक समिति (पीएसी) की बैठक जयललिता ने बुलायी थी। दो वरिष्ठ नेताओं के लिए यह बैठक एक दिन टाल दी गयी। फिर भी २६ जून की पीएसी बैठक में नेदुनचेझियन, तिरुनवुकरासु और एस रामचंद्रन ने न आकर विद्रोह प्रकट कर दिया। खंडित पीएसी ने जयललिता को इंका से चुनाव गठजोड़ का अधिकार दे दिया। विद्रोहियों की यह दलील नहीं मानी गयी कि पीएसी की बैठक के संयोजक नेदुनचेझियन थे और जयललिता को बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। २७ जून को यह विद्रोह दबाने के लिए पार्टी की कार्यकारी महासचिव की हैसियत से जयललिता ने पीएसी को ही भंग कर दिया।

कुल मिलाकर जयललिता की पार्टी अपने संकट से जूझ रही है। इसीलिए वह तत्काल चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन चुनाव होना है—चाहे सितंबर में हो या जनवरी में। चुनाव के बाद ही वैक्यूम और बवंडर का दौर खतम होगा। और तभी सही अर्थों में तमिलनाडु का जायका बदलेगा।

—वशिष्ठ

स्कॉटडेल, युएसूए निवासी श्रीमती केथलीन ब्लेकबर्न बंदर छाप काले दंतमंजन की ही सिफ़ारिश क्यों करती हैं?

"आपको यह बतानेके लिए मै यह पत्र लिख रही हूँ कि
आपका उत्पादन बंदर छाप काला दंतमंजन इस्तेमाल करनेमें मुझे कितना आनंद मिलता है.
दंतमंजन बेशक उत्तम श्रेणीका है और इसके गुण भी लाजवाब है.
मै बड़ी खुशीके साथ अपने स्नेहीयों से इस दंतमंजनकी सिफ़ारिश करती हूँ.... "

(श्रीमती ब्लेकबर्न के पत्रसे)

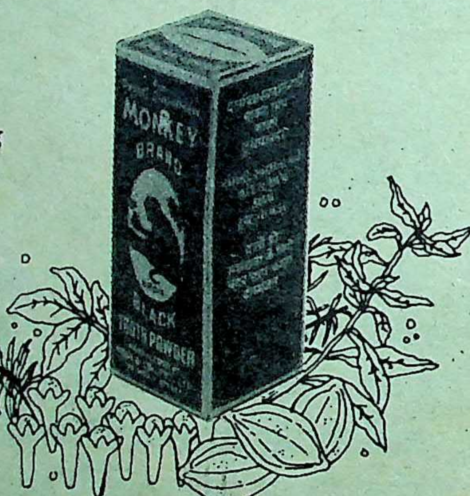

देश और विदेशमें हमारे लाखों ग्राहको में से यह केवल एक उदाहरण है, जो हमारे उत्पादनसे संतुष्ट है. क्यों?

इसका कारण यह है कि नोगीमें, हम गुणवत्तामें अपार विश्वास रखते है और बाकी सब अपने ग्राहकोंकी, सुझ-बुझपर छोड़ देते है, जैसे श्रीमती ब्लेकबर्न तथा अन्य...

और बंदर छाप काले दंतमंजन की इस कामयाबी का राज़ छुपा है इसके **आयुर्वेदिक फार्मुलेमें. मेन्थॉल, थाइमॉल,** (विशेष रूप से फ्रान्स से आयात किया हुआ), **लौंग तेल** तथा अन्य जड़ी-बूटियों की नपी-तुली मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है. इसे विशिष्ट कालावधि तक परिपक्व होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे परिपूर्ण सुगंध पैदा होती है. इस दंतमंजन में शामिल हर एक तत्त्व की दंतचिकित्सा में अपनी विशेष महत्ता है. थाइमॉल एक जन्तुनाशक तत्त्व है जो मसूड़ोंके लिए गुणकारी है: लौंग का तेल दांतों के दर्द से राहत दिलानेके लिए सुप्रसिध्द है और मेन्थॉल ठंडे स्वादवाला एक कोमल दर्दनिवारक है.

यही नहीं, इसमें हरडा के अतिरिक्त गुण भी शामिल है जो मसूड़ोंको जकड़नेमें मदद करती है और छालोंसे आराम पहुँचाती है. अंतमें, सबसे महत्त्वपूर्ण है इसका कोयला का आधार, जो बंदर छाप काले दंतमंजन को लोकप्रिय बनाता है - दांतोंको चमकदार और सफेद बनानेमें वचनबद्ध है. इसका कारण यह है कि कोयला दुर्गंधका नाश करता है और दातों को सफ़ेद बनाता है. इसीलिए बंदर छाप काला दंतमंजन आपके दांतोंको ज्यादा साफ और ज्यादा सफ़ेद रखता है.

तो फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि ७५ वर्षोंसे बंदर छाप काला दंतमंजन न केवल भारतमें बल्कि दुनियाभरमें प्रेमपूर्वक अपनाया गया है. क्योंकि श्रीमती ब्लेकबर्न की तरह अधिकतर लोग अपने दातोंकी सही देखभाल के लिए किसी और दंतमंजनपर भरोसा नहीं करते.

बंदर छाप
काला दंतमंजन
७५ वर्षों से
दुनियाभरमें विश्वसनीय

नोगी

सन १९११ से

P.S. ADVTS/EXEL/87/2

कार्टून

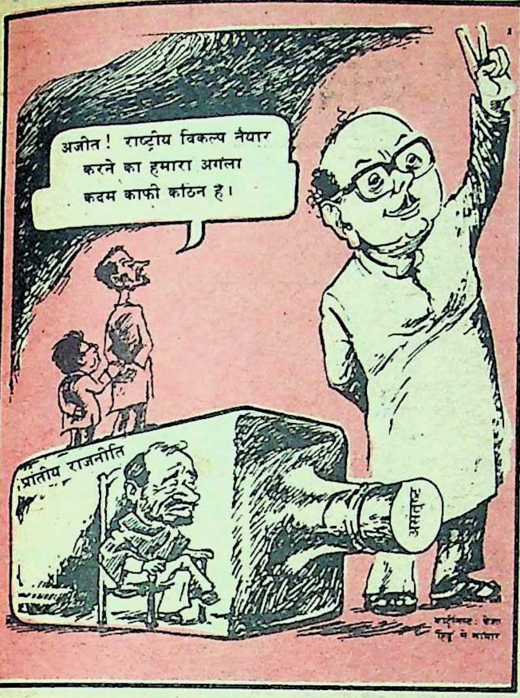
अजीत ! राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने का हमारा अगला कदम काफी कठिन है।
प्रांतीय राजनीति
असंतुष्ट

कार्टूनिस्ट : केशव
'हिंदू' से साभार

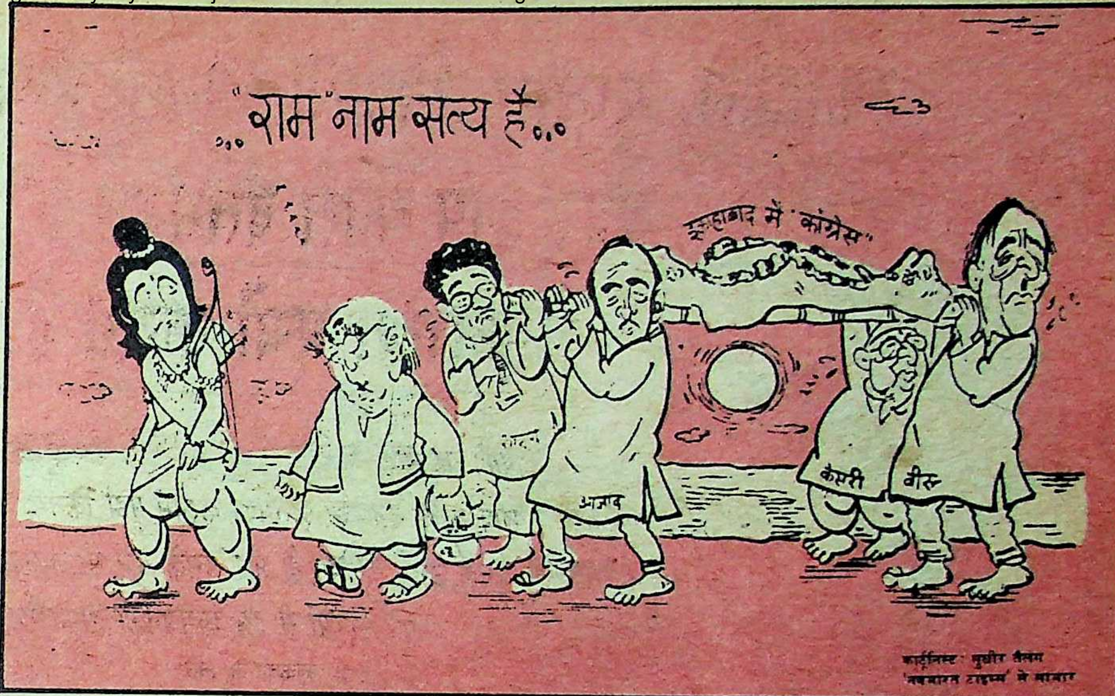
"राम" नाम सत्य है...
इलाहाबाद में "कांग्रेस"
आज़ाद
केसरी
वीस

कार्टूनिस्ट : सुधीर तैलंग
'नवभारत टाइम्स' से साभार

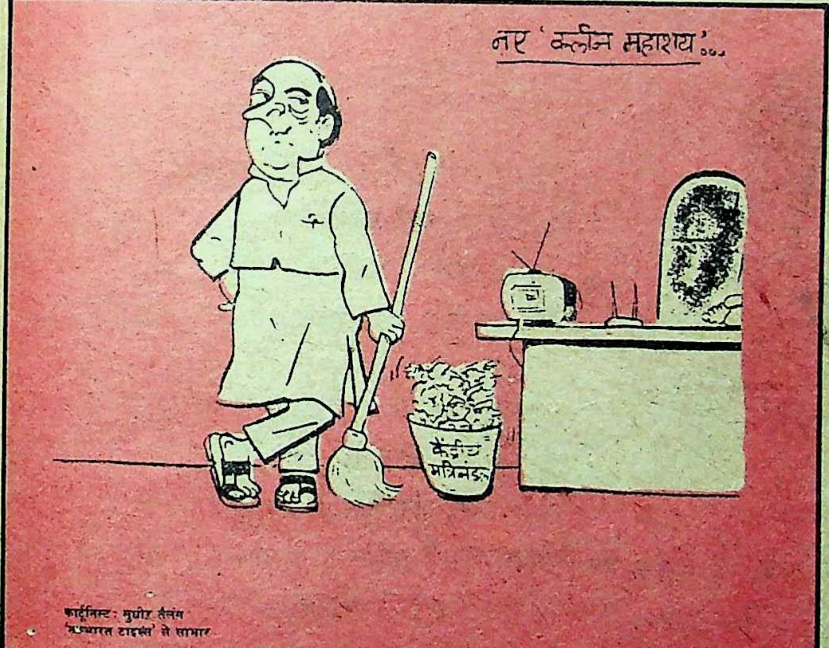
नए 'क्लीन महाशय'...
केंद्रीय मंत्रिमंडल

कार्टूनिस्ट : सुधीर तैलंग
'नवभारत टाइम्स' से साभार

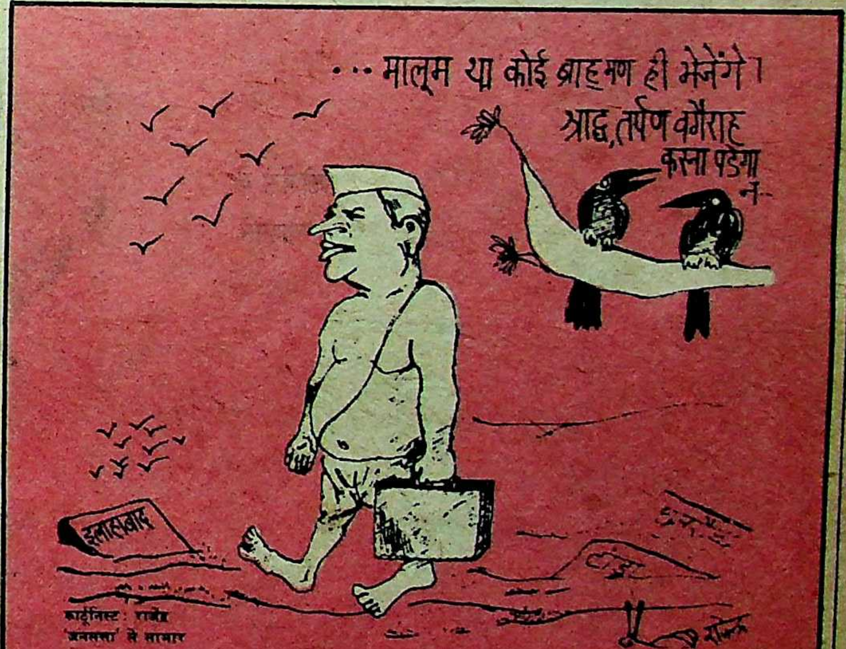
...मालूम था कोई ब्राह्मण ही भेजेंगे।
श्राद्ध, तर्पण वगैरह करना पड़ेगा
इलाहाबाद
राजेन्द्र

कार्टूनिस्ट : राजेंद्र
'जनसत्ता' से साभार

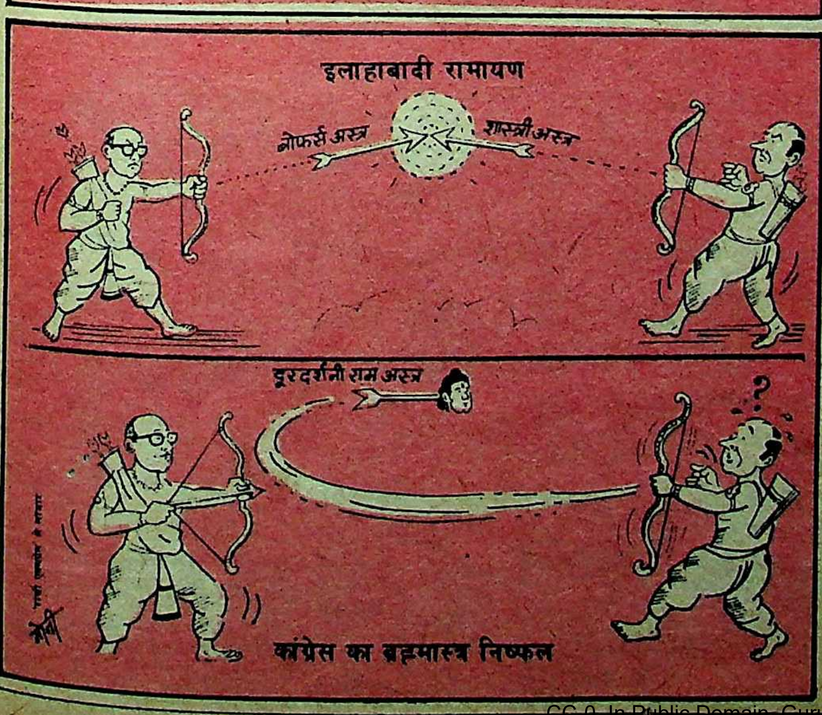
इलाहाबादी रामायण
बोफर्स अस्त्र
शास्त्री अस्त्र
दूरदर्शनी राम अस्त्र
?
कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र निष्फल

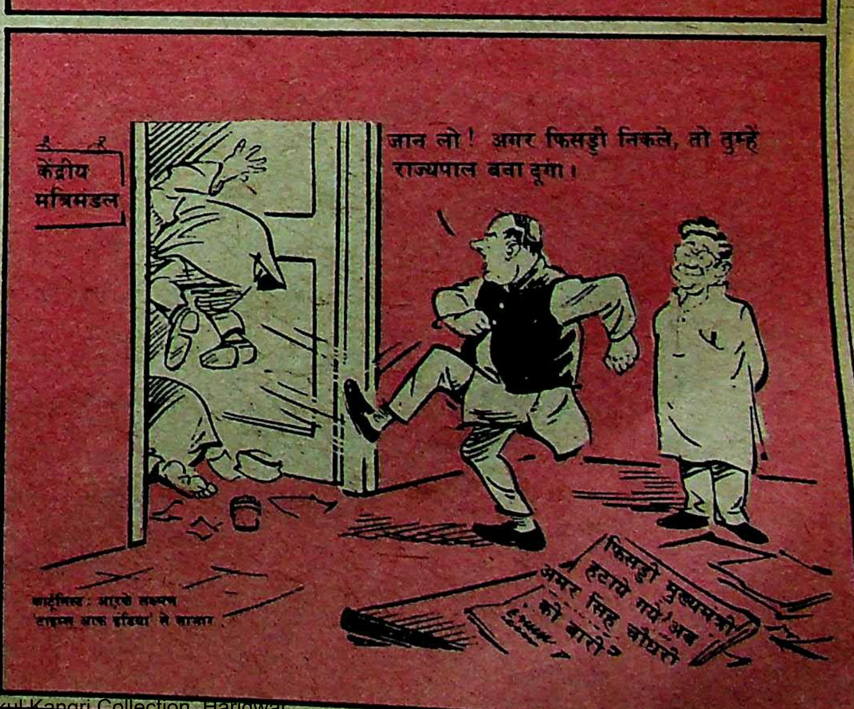
केंद्रीय मंत्रिमंडल
जान लो ! अगर फिसड्डी निकले, तो तुम्हें राज्यपाल बना दूंगा।
फिसड्डी मुख्यमंत्री हटाये गये। अब अमर सिंह चौधरी की बारी?

कार्टूनिस्ट : आर.के. लक्ष्मण
'टाइम्स ऑफ इंडिया' से साभार

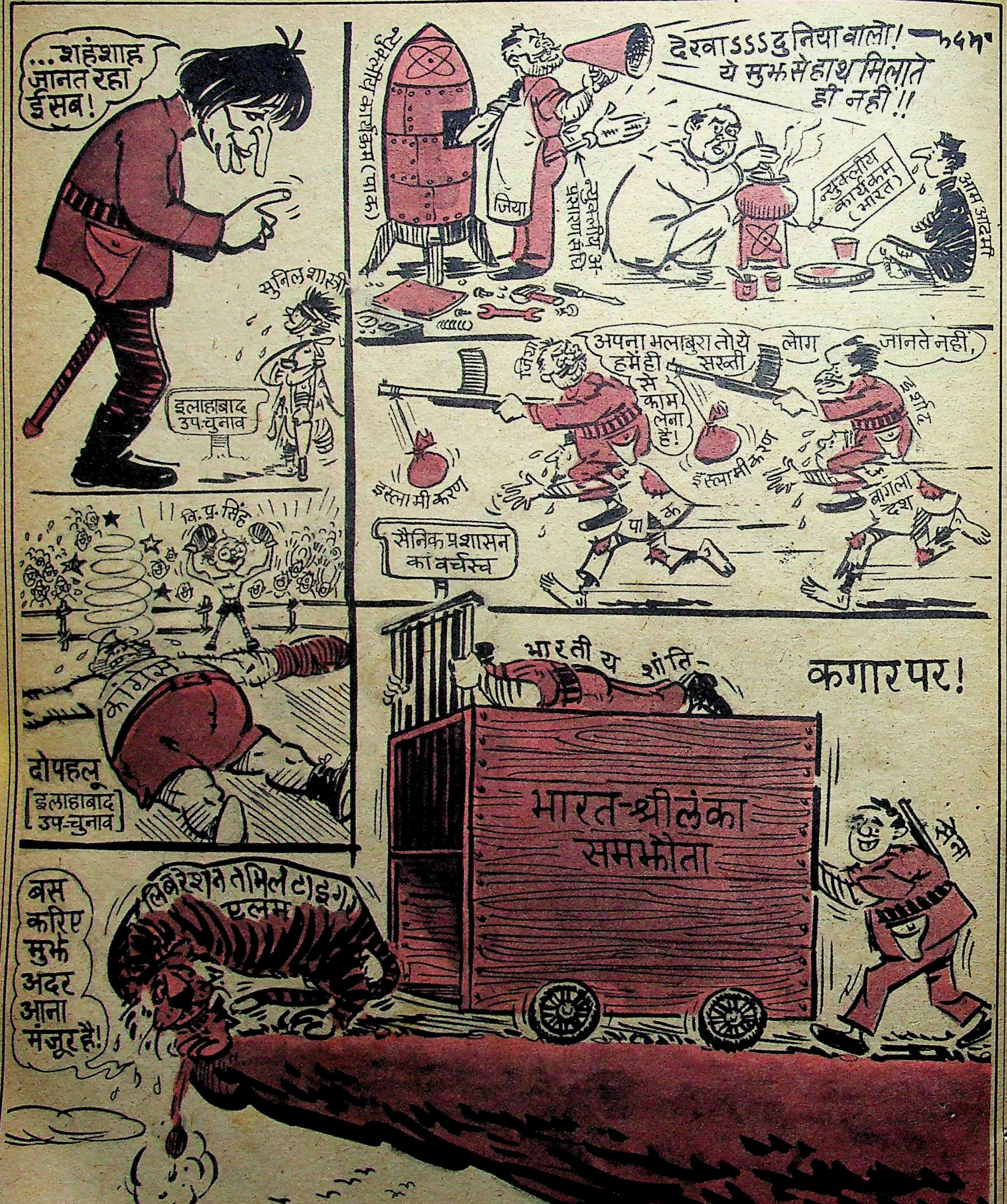
...शहंशाह जानत रहा ईसब!
सुनिल शास्त्री
इलाहाबाद उप-चुनाव
देखाऽऽऽ दुनिया वालो! ये मुझसे हाथ मिलाते ही नहीं!!
काक
परमाणु कार्यक्रम (पाक)
जिया
न्यूक्लीय अप्रसार संधि
न्यूक्लीय कार्यक्रम (भारत)
आम आदमी
अपना भला बुरा तो ये लोग जानते नहीं, हमें ही सख्ती से काम लेना है!
जिया
इरशाद
इस्लामीकरण
इस्लामीकरण
इस्लामीकरण
पाक
बांगला देश
सैनिक प्रशासन का वर्चस्व
वि. प्र. सिंह
कांग्रेस
दोपहलू [इलाहाबाद उप-चुनाव]
भारतीय शांति
कगार पर!
भारत-श्रीलंका समझौता
सेना
लिबरेशन तमिल टाइगर एलम
बस करिए मुझे अदर आना मंजूर है!

Rashmi
ZAFRANI PATTI
रश्मि
ज़र्दा
ज़ाफरानी पत्ती
सत्यपाल शिवकुमार
नया बाँस, देहली-110006

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब...

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में
वही परम्परागत स्वाद,
वाह! क्या लाजवाब.......

रश्मि
ज़र्दा

सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006

(वैधानिक चेतावनी — तम्बाकू स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

BLISS/DEL

विपक्ष के नेतृत्व का सवाल

वीपी सिंह का भविष्य

इलाहाबाद उपचुनाव में वीपी सिंह को जिताने के लिए विपक्ष ने जिस तरह डेरा डालकर एकजुटता, चौकसी और तत्परता के साथ अभियान चलाया, उसकी मिसाल अन्यत्र दुर्लभ है। लेकिन वीपी सिंह के नेतृत्व के प्रश्न को लेकर पूरे विपक्ष में जो बावेला मचा है, वह तो अभूतपूर्व है। आखिर यह सवाल इतने व्यापक विवाद का कारण क्यों बन गया? इससे विपक्ष की कैसी छवि उभरती है? और यह विवाद वीपी सिंह के भविष्य को कैसा रंग दे रहा है? इन प्रश्नों का सटीक उत्तर वीपी सिंह ही दे सकते हैं। लेकिन कैसे और कब?

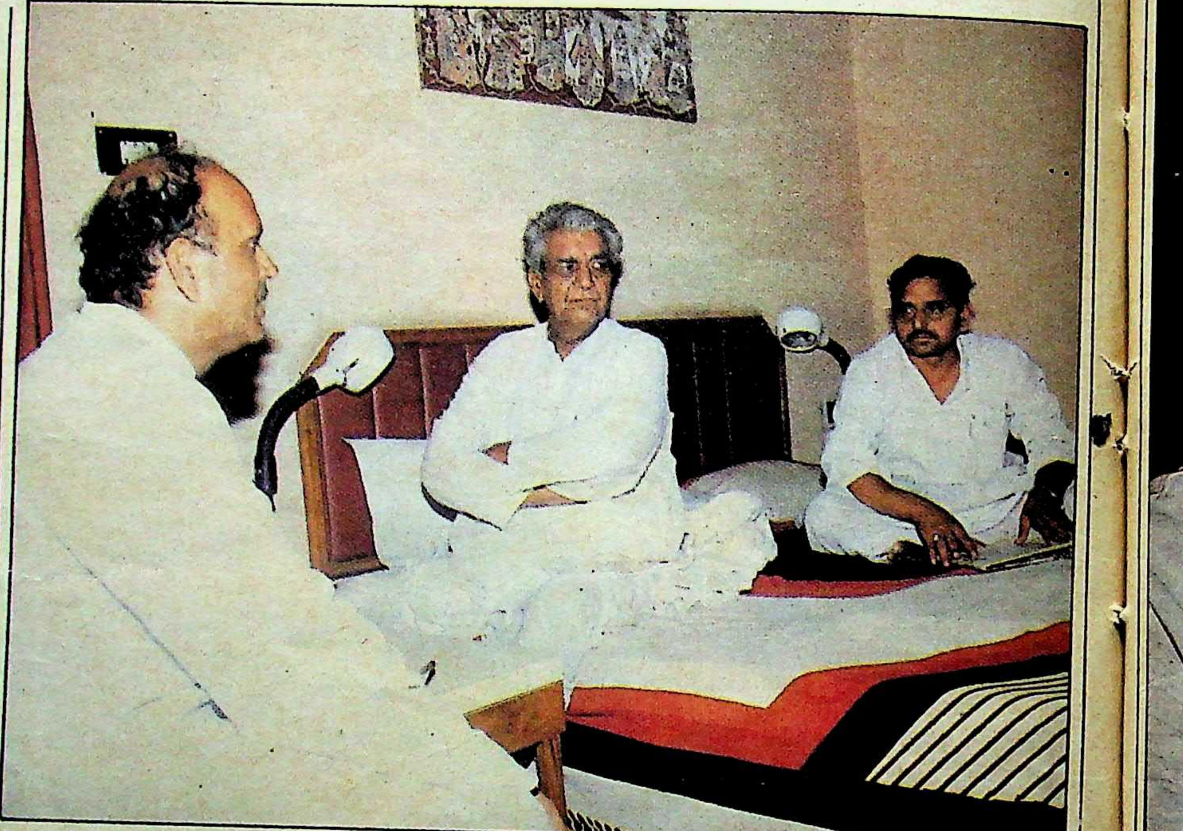

नेता स्वीकार: देवीलाल और मुलायम सिंह (पलंग पर पलथी मारे) के साथ वीपी सिंह

इलाहाबाद के ऐतिहासिक उपचुनाव ने कांग्रेस में ही हड़कंप नहीं मचाया है, बल्कि वीपी सिंह के साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर पहली बार खड़े संपूर्ण विपक्ष में भी उथल-पुथल पैदा कर दी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को इस जीत से खुशी नहीं है अथवा वह इससे लाभान्वित नहीं हुआ है। विपक्षी हौसले निश्चय ही बढ़े हैं। भविष्य की सफलता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इस उपचुनाव में जनमत संग्रह कांग्रेस के खिलाफ गया है। कांग्रेस हुकूमत पर विपक्ष द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों पर मतदाताओं ने अपने सही का निशान लगाकर शासक पार्टी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। किंतु इसी बीच भावी नेतृत्व के उभरे विवाद ने भारी खींचतान पैदा कर विपक्ष की संभावित एकता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

कदाचित विवाद का यह मुद्दा नया नहीं है। लोकदल-ब नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल पिछले कुछ महीनों से लगातार वीपी सिंह को विपक्ष का भावी प्रधानमंत्री घोषित करते आ रहे थे। किंतु उनकी यह बात विपक्ष के किसी अन्य नेता ने नहीं दोहरायी थी। अतः दूरदर्शन ने इलाहाबाद उपचुनाव की मतगणना पूरी होने के पहले ही जनता पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह से यह सवाल करके कि 'क्या वीपी सिंह भविष्य में भी आपके केंद्रीय नायक होंगे?' मानो मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ रख दिया। अचानक पूछे गये इस सवाल पर अजीत सिंह ने पहले तो सीधा उत्तर न देकर बात को घुमाने का प्रयास किया, किंतु जब प्रश्नकर्ता पीछे पड़ गया और 'हां' और 'न' में जवाब मांगने लगा, तो वह बगलें झांकने लगे। उनकी इस दुविधाग्रस्त स्थिति का साक्षात्कार उस समय देश के लगभग १५ करोड़ दर्शक कर रहे थे। कांग्रेस को शायद नवनिर्मित विपक्षी किले में पहली दरार डालने में यहीं पर सफलता प्राप्त हो गयी।

दुविधाग्रस्त मनःस्थिति केवल अजीत सिंह की ही नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष की है जिसने वीपी सिंह को जिताने के लिए जी-जान से कोशिश की। ७ संसदीय और ११ विधानसभायी उपचुनावों के नतीजों में कांग्रेस को मिली भारी पराजय ने उसके अंतर्विरोधों को जितना उजागर किया है, उससे कहीं अधिक उजागर विपक्ष के बीच मौजूद परस्पर अविश्वासों और अंतर्विरोधों को किया है। यहां तक कि प्रमुख जनमोर्चा नेता आरिफ मोहम्मद खां ने सांप्रदायिक दलों और उनके पक्षधरों की चुनाव प्रचार में सहायता लेने का प्रश्न उठाकर अपने ही शीर्षस्थ नेता को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

विपक्षी संदेह और संशय का प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस को अलविदा करने के बाद से वीपी सिंह का विपक्ष से रिश्ता कभी स्पष्ट नहीं हुआ। अपनी सभाओं और रैलियों में उन्होंने जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग लिया, वहीं वामपंथी पार्टियों को अपना 'स्वाभाविक सहयोगी' भी करार दिया। उनकी दुविधाजनक स्थिति आरंभिक बयानों और भाषणों से भी प्रकट थी, जिसमें वह भविष्य में कोई पद न लेने और चुनाव न लड़ने जैसी घोषणायें तो कर रहे थे, किंतु भारत भ्रमण, जनसभाएं करने का एक भी मौका नहीं चूक रहे थे। इसका प्रमुख कारण कदाचित यह था कि प्रारंभ में उनकी नजर कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की थी। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा-खासा भाग उनके साथ आकर मिल जायेगा।

वीपी सिंह के इस असमंजस का रंग विपक्ष पर भी चढ़ा था। वह इस दुविधा में था कि उनका कितना विश्वास करे, कितना साथ दे। यह स्पष्ट न था कि वह कांग्रेस में दो फांक करेंगे या उसकी (विपक्ष की) कतार में शामिल होंगे। जब कांग्रेस का आधा-अधूरा किला फतह करने में वीपी सिंह के मंसूबों पर पानी फिर गया, तब उन्होंने विपक्ष के साथ पंक्तिबद्ध होने की पहल की। स्थिति ने तब एक स्पष्ट रूप धारण किया जब चार राष्ट्रीय पार्टियों—जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स और जनमोर्चा का एक संयुक्त मोर्चा बना।

इलाहाबाद उपचुनाव एक प्रकार से विपक्ष के साथ उनकी एकता के सबसे मजबूत और ज्वलंत

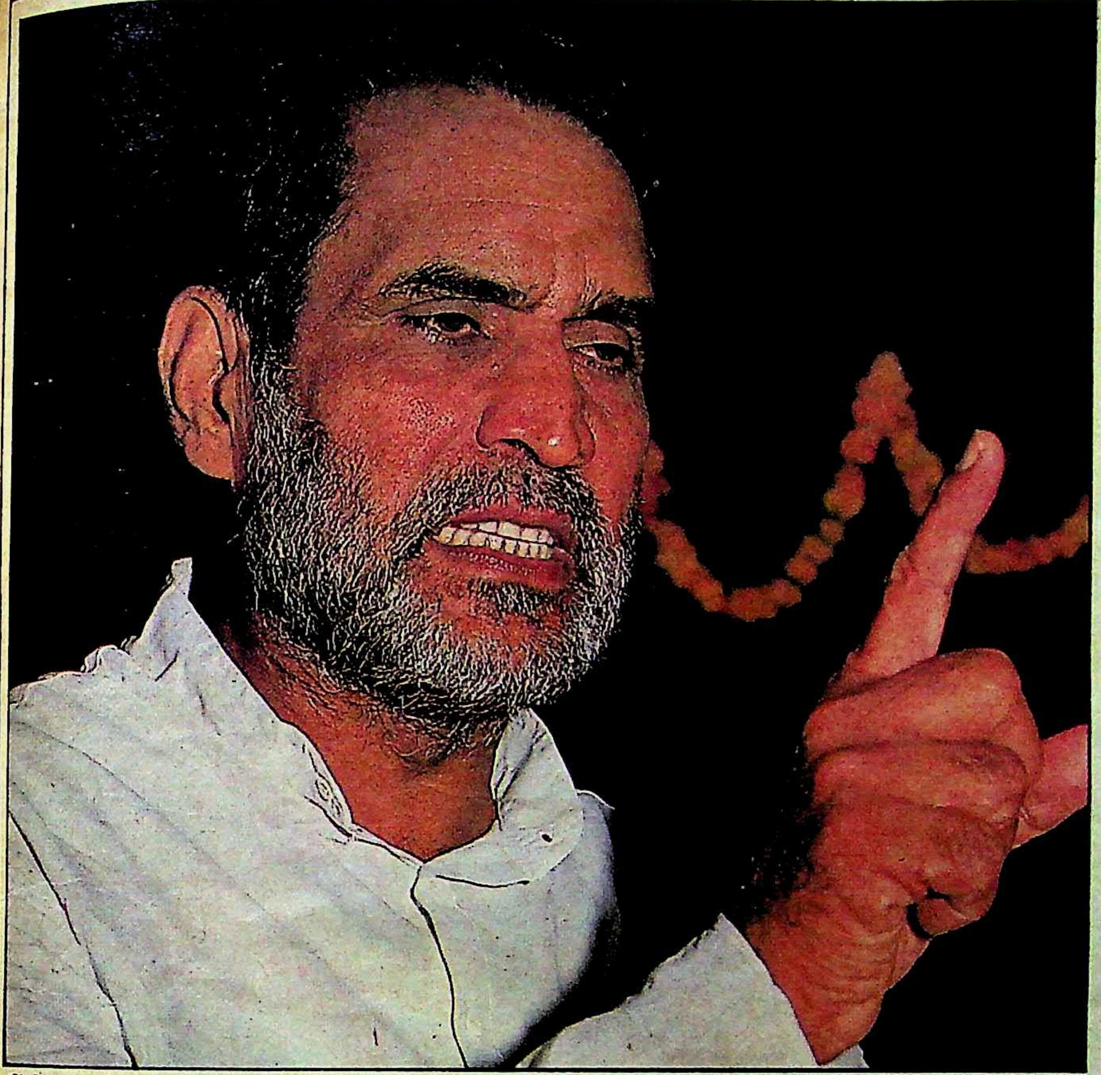

मैं नेता नहीं मानता : चंद्रशेखर

छाया : क्लाउन

उदाहरण के रूप में सामने आया। विपक्ष द्वारा लड़ा गया यह एक संयुक्त चुनाव था, जिसमें विपरीत ध्रुवों पर टिकी पार्टियां—भाजपा और माकपा भाकपा भी एक साथ थीं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से ही विपक्षी खेमों में हलचल मच जाना यदि पूर्णतया आश्चर्यजनक नहीं, तो इस बात का द्योतक अवश्य है कि विपक्ष के सिरमौर नेता की गद्दी तक पहुंचने के लिए वीपी सिंह का एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। प्रश्न यह है कि क्या वीपी सिंह ऐसा कर अंततः कांग्रेस का विकल्प बनेंगे? यह भी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कौन-सा मार्ग अपनाना पड़ेगा?

मौजूदा विवाद : भावी नेतृत्व को लेकर उठे वर्तमान विवाद ने लगभग सभी विपक्षी दलों को ऐसे समय अपनी चपेट में ले लिया है, जब कि हर्षोल्लास और नये जोश-खरोश की अपेक्षा थी। ऐसा न होकर विपक्ष का जो परिदृश्य आज दरपेश है, उसके दो मूल मुद्दे हैं। एक, नेतृत्व को लेकर और दूसरा नीतियों को लेकर।

यद्यपि सभी दल इस बात को स्वीकारते हैं कि न केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह का कद निरंतर बढ़ा है, वरन उनमें विपक्ष का केंद्रबिंदु बनने की सर्वाधिक संभावना भी है। किंतु अधिकांश का मत है कि वर्तमान समय संघर्ष करने और विपक्षी एकता की जड़ मजबूत करने का है। नेता की छवि मांजने-चमकाने और प्रचारित करने का नहीं है। जनता पार्टी नेता चंद्रशेखर ने दोटूक तरीके से कहा है, “राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से किसी को भावी प्रधानमंत्री घोषित करना बुद्धिमानी का काम नहीं है।” लोकदल-ब अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा ने उपचुनाव नतीजों के तुरंत बाद ‘माया’ से बातचीत के दौरान कहा था, “उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए एक चुनौती हैं कि वह विकल्प तैयार करे और यह विकल्प केवल व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति और नीति दोनों का होना चाहिए।”

इन दो वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया पर जहां कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने उन पर वैर-द्वेषग्रस्त होने और कुरसी के स्वयं दावेदार बनने का आरोप लगाया है, वहीं अधिकांश विपक्षी नेताओं ने प्रकारांतर से लगभग यही बात दोहरायी है। फर्क केवल इतना है कि कुछ खुलेआम बोल रहे हैं और कुछ परदे के पीछे से।

व्यक्तित्व को दरकिनार करनेवालों की दलील है कि १६७७ के जेपी आंदोलन में किसी व्यक्तित्व को न उभारकर एक देशव्यापी आंदोलन की दाग बेल डाली गयी थी जो बाद में कांग्रेस शासन की जड़ खोदने में मददगार साबित हुई थी। इसके उलटे नेतृत्व के प्रश्न को प्रमुखता देने वालों का दावा है कि किसी शीर्षस्थ नेता का पूर्व चुनाव न करने की जो भूल जनता पार्टी ने की थी, उसके फलस्वरूप उसके अनेक दावेदार हो गये थे। इसी भूल की कीमत जनता पार्टी ने दिल्ली की गद्दी खाली करके चुकायी थी।

मौजूदा विपक्षी परिदृश्य में नेतृत्व का मुद्दा भी बहुआयामी है। वीपी सिंह की छवि पिछले एक वर्ष में साफ-सुथरी और विश्वसनीयता के रूप में तो अवश्य उभरी है, किंतु सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान और निर्विवाद विपक्षी नेता के रूप में नहीं। विपक्ष में मौजूद आलोचक उन्हें कांग्रेस संस्कृति का ही एक अंग और एक ही थैली के चट्टे-बट्टे करार देते हैं, वहीं अन्य लोग अनेक धुरंधर विपक्षी नेताओं का नाम सूची में आगे नहीं, तो पीछे भी नहीं रखना चाहते। इनमें चंद्रशेखर और बहुगुणा के अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, रामकृष्ण हेगड़े, ज्योति बसु, एनटी रामाराव और देवीलाल जैसे पुराने मंजे नेताओं का नाम लिया जाता है। इस मत के दावेदारों का कहना है कि वीपी सिंह यदि इन शीर्षस्थ विपक्षी नेताओं के समकक्ष होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कद और काबीलियत का परिचय देना होगा और यह भी तय करना होगा कि ‘जनमोर्चा’ को वह गैर-राजनीतिक संगठन बनाये रखेंगे अथवा किसी स्वतंत्र राजनीतिक दल का रूप देंगे। क्योंकि अब वह सीधे-सीधे विपक्षी राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। इसके पूर्व तक तो वह मात्र एकसूत्री कार्यक्रम ‘भ्रष्टाचार और राजीव हटाओ’ चला रहे थे। विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने के लिए उन्हें एक सुनिश्चित नीति और कार्यक्रम पेश करना लाजिमी है।

जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता का कहना है कि नेतृत्व के प्रश्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नीतियों का प्रश्न है। उनके कथन की पुष्टि करते हुए मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद कहते हैं, “कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना एक बेवकूफी भरा प्रयास है। सवाल आज एक प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का विकल्प पेश करने का नहीं है। ऐसी तमाम कोशिशें तब तक नाकाम साबित होंगी जब तक हम एक वैकल्पिक आर्थिक नीति और कार्यक्रम न पेश करें। जरूरी है कि पहले आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की बुनियाद पर कारगर विकल्प तैयार किया जाये। यह किसी खास व्यक्ति को अगला प्रधानमंत्री ‘प्रोजेक्ट’ करने भर से नहीं होगा।” लगभग यही बात जनता पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह जो इस मुद्दे को उभारने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम के केंद्रबिंदु बने थे, ने ‘माया’ से कही, “वीपी सिंह को नेता स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं। किंतु सवाल केवल नेता चुने जाने भर का नहीं। इससे जुड़े अनेक मुद्दों का है, मसलन संयुक्त पार्टी बनेगी अथवा संयुक्त कार्यक्रम, किस तरह संघर्ष होगा, यदि संयुक्त पार्टी बनेगी, तो उसका कौन नेता होगा तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका होगी?”

लोकदल-अ से जनता पार्टी में आये एक नेता ने इससे अधिक आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा, “देवीलाल के लिए तो बड़ा आसान है कि वह वीपी

सिंह को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दें और स्वयं को संसदीय दल का अध्यक्ष। किंतु जब संयुक्त रूप से विपक्षी मुहिम चलाना होता है, तो एकपक्षीय और मनमाना एलान लाभ की जगह हानिकर सिद्ध होता है।"

देवीलाल के इस एलान से विपक्षी खेमे में खलबली मचना स्वाभाविक था। देवीलाल के इस रवैये पर टिप्पणी करते हुए संयुक्त मोर्चे के एक वरिष्ठ नेता ने 'माया' को बताया, "देवीलाल ने हमारी चार पार्टियों (जनता, लोकदल-अ, कांग्रेस-स व जनमोर्चा) का मोर्चा बनते देख अपने को अलग-थलग पाकर झटपट चाणक्य नीति चली। किसान के बेटे को प्रधानमंत्री और हरिजन के बेटे को राष्ट्रपति की गद्दी सौंपने का ख्वाब देखने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने किसान बेटे की बलि चढ़ाकर राजा साहब को गद्दीनशीं करने का जो पांसा फेंका, वह उनकी समझी-बूझी चाल थी।"

हम सहयोग करेंगे: वीपी सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ

छाया: मनमोहन शर्मा

देवीलाल पर ऐसे आरोप चाहे जो भी लगते हों, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ कारगर विपक्षी एकता कायम करने के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। हरियाणा में उनकी अगुवाई में विपक्ष को मिली अभूतपूर्व विजय ने न केवल उनकी, बल्कि समूचे विपक्ष की छवि को निखारा था। फिर उन्होंने प्रमुख विपक्षी दलों की सूरजकुंड में बैठक भी बुलायी थी। किंतु इलाहाबाद उपचुनाव के वक्त यह मुद्दा दुबारा उठाकर उन्होंने स्थिति को नाजुक बना दिया है।

वैसे वीपी सिंह का झंडा उठाने वाले देवीलाल अकेले नहीं हैं। उनकी कतार में जनता पार्टी के अनेक नामीगिरामी नेता, जैसे—बीजू पटनायक और रामकृष्ण हेगड़े भी शामिल हैं। यद्यपि हेगड़े, देवीलाल और बीजू पटनायक की भांति एलानिया वीपी सिंह का नाम नहीं उछाल रहे हैं, किंतु उनकी मंशा भी इन दोनों नेताओं से मेल खाती है। लगता है, हेगड़े का यह रवैया उनके सिंहासन का पाया कमजोर करनेवाले पूर्व पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर और वर्तमान अध्यक्ष अजीत सिंह को सबक सिखाने के लिए है। ज्ञात रहे कि जनता पार्टी में लोकदल-अ के विलय को लेकर जब जबर्दस्त उठापटक हो रही थी, तब हेगड़े ने देवीलाल के साथ मिलकर एक नयी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, के गठन और वीपी सिंह को अपना शीर्षस्थ नेता बनाने की बात चलायी थी। किंतु कर्नाटक में पार्टी विधायकों द्वारा मुसीबत खड़ी की जाने के कारण उन्हें अपना अभियान धीमा करना पड़ा था। इसी प्रकार आंध्र के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने राष्ट्रीय संघीय मोर्चा बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें घटकों के दावों तथा चुनावी मसलों को हल करने के लिए संघीय संसदीय दल बनाने का भी प्रस्ताव है। लेकिन नेता के प्रश्न ने इस प्रस्ताव को भी अधर में लटका दिया है।

विरोध: विपक्षी दलों में वीपी सिंह की नामजदगी का विरोध करने वालों का कहना है कि जनसंघर्ष द्वारा शीर्षस्थ नेता का उदय होता है, न कि किसी के नाम उछालने से। अजीत सिंह भी प्राथमिकताओं की बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि उनका तात्कालिक उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना और कांग्रेस का सक्षम विकल्प तैयार करना है। राजीव गांधी का (विकल्प) नहीं। इसी के तहत वह और अ विपक्षी नेता क्रम-नियम की बात करते हैं।

"मॉडेलिटी (क्रम-नियम) महज धोखाधड़ी होती है" वीपी सिंह के कट्टर समर्थक देवीलाल ने 'माया' से बात करते हुए कहा, "दस जीरो का तब तक कोई मूल्य नहीं होता है जब तक कि उसके पहले एक (१) न लगाओ। अर्थात् जो जनता से जुड़ा हो, जनता की आस्था-आकांक्षाओं का प्रतीक हो। जैसे आजादी की लड़ाई में गांधीजी, ७४ में जेपी की भूमिका। इसके बिना पार्टियों की जोड़तोड़ और धालमेल एक निरर्थक कवायद सिद्ध होगी।"

विपक्ष में व्याप्त इस मतभेद, संशय और अंतर्कलह को देखते हुए सर्वोपरि विपक्षी नेता के रूप में वीपी सिंह के उभरने की संभावना फिलहाल धुंधली दिखायी दे रही है। यदि एक गुट उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार घोषित करने में संलग्न है, तो दूसरा नीतियों और कार्यक्रमों का मुद्दा उठाकर नेतृत्व के प्रश्न को हाशिये पर डालने में लगा है। वीपी सिंह के लिए इनके बीच अपने को मान्यता दिलाने का काम नदी के दो तटों के बीच पुल बनाने जैसा ही होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष भी अपने स्वरूप में एक नहीं, तीन स्तरों पर बंटा है। ये तीन स्तर हैं: (१) एकता और एकीकरण की संभावना वाली पार्टियां मसलन-जनता पार्टी, लोकदल-ब, कांग्रेस-स आदि (२) अपना अस्तित्व बरकरार रखने की नीति और कार्यक्रम के आधार पर एकजुट हो चुनावी तालमेल में विश्वास करने वाली पार्टियां, जैसे वामपंथी पार्टियां और भाजपा (३) क्षेत्रीय पार्टियां मसलन तेलुगुदेशम, असमगण परिषद, अन्नाद्रमुक, अकाली दल आदि। इससे भी संगीन बात यह है कि विपक्ष की अधिकांश पार्टियों में आपसी रस्साकशी और उठापटक का दौर जारी है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर विवाद के अलावा कर्नाटक में उसकी सरकार तक पर ग्रहण लगने का संकेत स्पष्ट है। भाजपा की राजस्थान और मप्र इकाइयों में शीतयुद्ध छिड़ा है। माकपा और भाकपा प० बंगाल और केरल में साझा सरकार में शामिल होने के साथ स्थानीय चुनाव आदि में तलवारें भांजती रहती हैं। अन्नाद्रमुक एमजीआर के वारिस के सवाल पर दो फांक हो गया है। और-तो-और वीपी सिंह के कट्टर समर्थक देवीलाल एक ओर हैं, तो उनके अध्यक्ष बहुगुणाजी दूसरी ओर।

विपक्ष के वर्तमान परिदृश्य में सर्वोच्च नेता के दावेदार को जिस सूझबूझ, कुशलता और समतावादी दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए, उसका वीपी सिंह में उभर कर अभी आना बाकी है। इसका साक्षी इलाहाबाद का उपचुनाव है, जिसमें विपक्ष के तीनों स्तरों की संपूर्ण भागेदारी के बावजूद ऐसा आभास हुआ कि वीपी सिंह अभी भी 'एकला चलो' की नीति अपनाये हुए हैं। "वीपी सिंह विपक्षी उम्मीदवार जरूर थे। किंतु उनके प्रमुख सिपहसालार और अगुवा कांग्रेस से आये लोग ही थे। जो कुछ थोड़ी बहुत कसर थी, उसे उनकी ठाकुर बिरादरी ने अपना वर्चस्व कायम करके पूरा कर दिया था।" यह प्रतिक्रिया इलाहाबाद के चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाले एक समर्पित विपक्षी कार्यकर्ता की थी। वीपी सिंह को अपनी इस छवि से मुक्त होने के लिए घोर प्रयास करना पड़ेगा।

किंतु जैसा कि प्रत्यक्ष है, अभी वह ऐसी कोई कोशिश करते नजर नहीं आ रहे हैं। विजय के पश्चात देश के विभिन्न भागों में अपने जारी दौरों में

नेतृत्व का सवाल अप्रासंगिक : हेमवती नंदन बहुगुणा

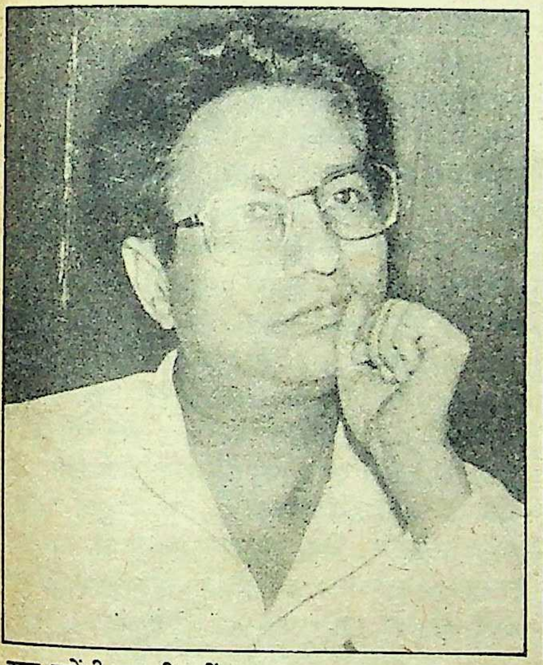

क्या कहें ? : अजीत सिंह

वह या तो अकेले अथवा अपने परम विश्वस्त और वीर बहादुर सरकार में मंत्री रह चुके संजय सिंह के साथ जा रहे हैं। उनकी जनसभाओं में विपक्षी पार्टी के नेताओं की संख्या नहीं के बराबर होतीं है। किंतु यह भी सच है कि उनकी सभाओं में लोगों का जोश-खरोश देखने योग्य होता है। लोगों को वीपी में जेपी का अहसास होने लगा है।

ऐसा लगता है कि वीपी सिंह ने यह कदम (देशभ्रमण का) सोच-समझ कर उठाया है। विपक्षी दलों की आगामी संभावित संयुक्त बैठक में उनका मोलभाव इससे बढ़ेगा, यह राजनीति के कुशल खिलाड़ी वीपी सिंह भलीभांति समझते हैं। विपक्ष भी चौकन्ना है। नतीजंतन फिलहाल वह वीपी सिंह को हाथोहाथ उठा कंधे पर बिठाने की प्रक्रिया से अपना दामन बचा रहा है। उसकी इस रणनीति के पीछे अपनी मोलतोल की स्थिति बरकरार रखना है। ज्ञात रहे कि भविष्य में जब भी विपक्षी एक जुटता का प्रश्न उभरेगा, तब शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य नेताओं की भूमिका, पदों, अधिकारों की समस्या भी सामने आयेगी। ऐसे समय में भी दल या नेता अधिकाधिक लाभ पाने के लिए सचेष्ट रहेंगे। "वीपी के नेतृत्व को लेकर विपक्ष में आज नहीं तो कल विवाद उठना स्वाभाविक था। इलाहाबाद उपचुनाव के होते ही यह गोला दाग दिया जायेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्योंकि गत माह आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम के महानाडु समारोह के दौरान विपक्षी एकता और नेतृत्व के प्रश्न पर सर्वसम्मत निर्णय लेने के लिए जुलाई माह में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित करना तय हुआ था। इसके आयोजन की जिम्मेदारी एनटी रामाराव को सौंपी गयी थी। इस प्रकार वर्तमान विवाद समय से पूर्व उभार कर विपक्षी एकता में दरार पैदा की गयी है। यह काम किसी और का नहीं, कांग्रेस का है," यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के एक विधायक ने 'माया' से बातचीत के दौरान की।

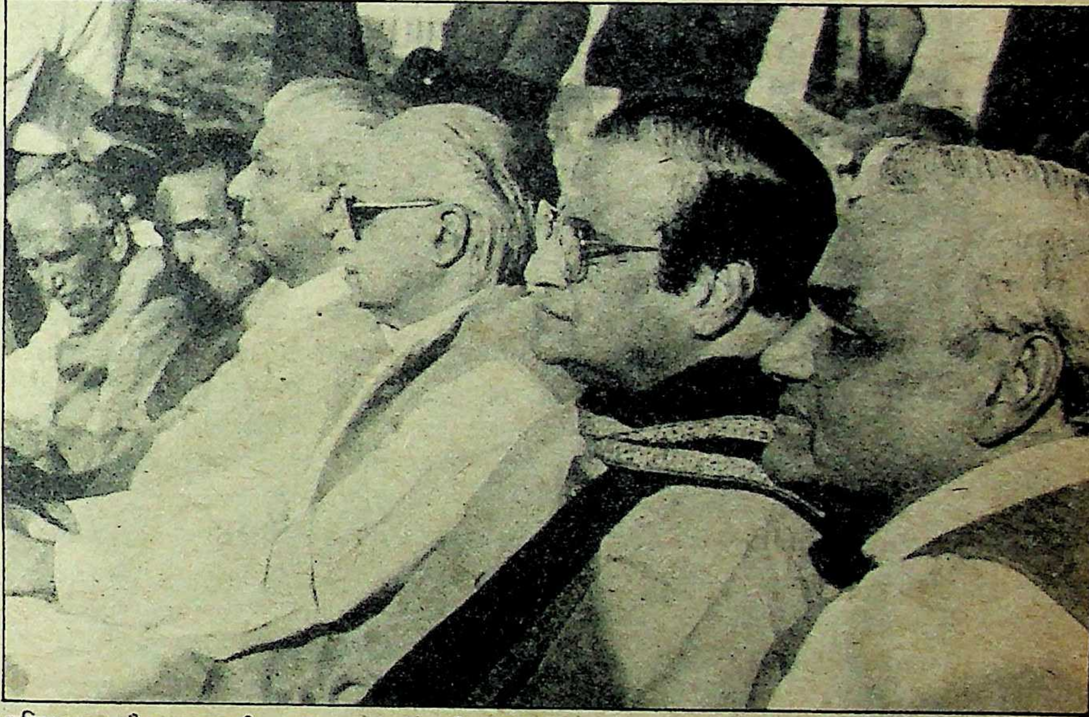

दुविधा का दौर : अटलजी, रामाराव, अडवाणी, देवीलाल एक सभा में

उठते सवाल : प्रश्न यह है कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद संभावना क्या बनेगी ? विपक्षी एकता के दो संभावित रूपों की चर्चा है। एक, संयुक्त विपक्षी पार्टी और दूसरा, एक संगठित विपक्षी मोर्चा। दोनों की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। जहां तक संयुक्त (एकीकृत) पार्टी का प्रश्न है, उस पर रजामंद तो सभी हैं, पर जनता पार्टी के पिछले कटु अनुभव के आधार पर कोई भी पार्टी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती। इसकी अपेक्षा विपक्ष का संयुक्त मोर्चा अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है। भाजपा अध्यक्ष एलके अडवाणी, माकपा महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद और जनता पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह इसके समर्थक हैं। जपा नेता बीजू पटनायक एक कदम आगे बढ़कर न केवल विपक्ष की एक संघीय पार्टी के गठन पर जोर दे रहे हैं, बल्कि वीपी सिंह को उसका संयोजक बनाने का भी प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। किंतु इन दोनों स्थितियों एकीकृत पार्टी और संघीय पार्टी में विवाद नेतृत्व को लेकर भी उठने की संभावना है और विशेष नीतियों को लेकर भी। क्योंकि विपरीत ध्रुवों पर बैठी वामपंथी पार्टियां और भाजपा क्या एक मंच पर उतर सकेंगी ? जबकि लालकृष्ण अडवाणी ने हाल ही एलान किया है कि विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर उनकी पार्टी का वामपंथी पार्टियों से तालमेल होना असंभव है। यही बात कम्युनिस्ट नेताओं ने भी भाजपा के संबंध में दोहरायी है। किंतु अधिकांश विपक्षी नेताओं का यह मानना है कि जिस प्रकार वीपी सिंह के चुनाव में ये दोनों विपक्षी धड़े एकजुट हुए थे, उसी प्रकार विशेष राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वामपंथ और दक्षिणपंथ में सहयोग असंभव नहीं होगा।

जाहिर है, जल्द ही विपक्ष में नये राजनीतिक समीकरण उभरेंगे। इसका केंद्रबिंदु एक ओर जहां नीतियां और कार्यक्रम होंगे, वहीं दूसरी ओर नेतृत्व। महत्वाकांक्षाओं, निजी लोभ-लाभ और लालसा के चलते यदि बातचीत से सहमति नहीं बनी, तो विपक्षी पार्टियों में खाई पड़ना अवश्यंभावी होगा। नतीजतन विपक्षी पार्टियों का पुनः गठन और ध्रुवीकरण होगा। अफवाह पहले ही फैल रही है। एक ओर अरुण नेहरू और आरिफ आदि की वीपी सिंह से अलहदा होने की बातें सुनाई पड़ रही हैं, तो दूसरी ओर बहुगुणा गुट के और तीसरी ओर चंद्रशेखर गुट के अलग होने की बात। वर्तमान विपक्ष के सर्वोपरि नेता वीपी सिंह होंगे या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस मुद्दे पर उठापटक के केंद्रबिंदु वही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सर्वोत्तम व्यक्ति : मनीषी राजनीतिज्ञ और जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर मधु दंडवते वीपी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में विपक्षी नेताओं में सर्वोत्तम व्यक्ति मानते हैं। प्रो० दंडवते ने देश की

लखनऊ का नया जायका

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजनीतिक अनुभवों में बीते महीने की २४ तारीख ने एक नया जायका जोड़ दिया। यह जायका उस इत्तफाक से पैदा हुआ जब इलाहाबाद उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार लखनऊ आये विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुख्यमंत्री की कुरसी पर १००५ दिन की कब्जेदारी का नया कीर्तिमान बनाने के बाद अपना इस्तीफा लेकर राजभवन आये वीर बहादुर सिंह को लोगों ने रूबरू देखा। यही सबब था कि उस दिन लखनऊ का राजनीतिक तापमान शिखर तक चढ़ गया। मगर ऐसा बेवजह नहीं हो गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाये जाने के बाद वीपी सिंह ने अपना अलग खेमा गाड़कर इंका से बगावत की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी। तब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने अपने इस संकल्प का एलान किया था कि वह उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की राजनीति का पांव जमने नहीं देंगे। यह इत्तफाक ही था कि २४ जून को जिस वक्त वीपी सिंह का विजय जुलूस चारबाग रेलवे स्टेशन से होता हुआ विधानभवन के पास पहुंचा, ऐन उसी वक्त वीर बहादुर सिंह अपना इस्तीफा देकर राजभवन से निकले। सचिवालय के पास विजय जुलूस में तत्काल यह बात फैल गयी कि वीर बहादुर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। फिर तो जुलूस में शामिल लोग ही नहीं, उन्हें देखने-सुनने के लिए उमड़ी भीड़ भी अद्भुत उत्साह से आंदोलित हो उठी। नारे गूंज उठे, 'वीर बहादुर चले गये, अब राजीव की बारी है। उत्तर प्रदेश जीता है, अब दिल्ली भी जीतेंगे।' माहौल से साफ हो गया कि लोग वीर बहादुर के हटने को वीपी सिंह की दूसरी बड़ी विजय मान रहे हैं।

वीपी सिंह के लखनऊ आगमन पर जितनी भीड और उत्साह की अपेक्षा की गयी थी, वह नहीं थी। तब भी सुबह १० बजे जब वह इलाहाबाद से ट्रेन द्वारा लखनऊ पहुंचे, लगभग एक हजार की भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस भीड़ में सभी दलों के दूसरे दर्जे के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन सर्वाधिक उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में देखा गया। अपनी अल्पसंख्या के बावजूद भाकपा और माकपा के कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर उत्साह दिखाया। वैसे, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष समरपाल सिंह और महामंत्री राकेश सिंह राना भी स्वागत जुलूस में गये थे, लेकिन छात्रों की कोई भीड़ उनके साथ नहीं थी।

सभी दलों के झंडे लहराते हुए जुलूस आधा दर्जन स्वागत द्वारों से होता हुआ राजभवन कालोनी स्थित वीपी सिंह के आवास पहुंचा। मार्ग में ४ जगहों पर वीपी सिंह ने अपने सम्मान में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। अपने निवास पर एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए वीपी सिंह ने उत्साह के साथ कहा, "अभी हमने ७ दरवाजों में से एक द्वार तोड़ा है, आगे और द्वार तोड़ने हैं। हमारी फौज (जनता) १९९० तक दिल्ली दरवाजा तोड़ने में कामयाब जरूर होगी।"

वीपी सिंह के आगमन और उनके स्वागत के प्रति विपक्षी दलों ने जो रुख प्रदर्शित किया, उससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि वे अभी उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं हैं। राजा मांडा के स्वागत की तैयारी का जिम्मा मुख्यतः जनमोर्चा नेता जफर अली नकवी पर था। परंतु नकवी से विपक्षी दलों के नेताओं ने सहयोग नहीं किया।

मजे की बात यह है कि लगभग २० बसों तथा आधा दर्जन स्वागत द्वारों की व्यवस्था का जिम्मा लेने वाले लोकदल-ब के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य तथा ठाकुर ट्रांसपोर्ट के मालिक राजकिशोर मित्र लापता हो गये। न तो उनकी बसों का कहीं पता था, न स्वागत द्वारों का और न खुद उनका। वह उस समय भी नहीं दिखायी पड़े, जब जुलूस उनके निवास के सामने से होकर गुजरा। कहते हैं, उन्हें लोकदल-ब के नेता मुलायम सिंह यादव ने 'टाइट' कर दिया था। मुलायम सिंह ने खुद भी २४ जून की सुबह इटावा का रास्ता पकड़ लिया था। अलबत्ता फर्ज अदायगी में उनकी पार्टी के नेता मुख्तार अनीस जुलूस में, अंतिम पड़ाव के थोड़ा पहले, शरीक होकर वीपी सिंह के घर तक गये थे।

लोकदल-ब की ताजा नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, लोकदल-ब के नेता जनेश्वर मिश्र द्वारा इलाहाबाद के कटरा बाजार में आयोजित विजय समारोह में शामिल नहीं हुए थे।

जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह तो चंद्रशेखर द्वारा पुणे में दिये गये उस बयान के बाद ही ठंडा पड़ गया था जिसमें उन्होंने कहा था, "विश्वनाथ प्रताप सिंह उतने अधिक महत्व के काबिल नहीं, जितना उन्हें दिया जा रहा है।"

वीपी सिंह के लखनऊ आगमन को उनके कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक स्वरूप भले दे दिया हो, लेकिन बकौल राजा मांडा यह उनकी निजी यात्रा थी। वह अपनी पार्टी के तीन सहयोगियों के घर शादियों में शरीक होने आये थे। लेकिन असलियत क्या है? इसके उजागर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

—सुरेश द्विवेदी

राजनीतिक आकांक्षा और वक्त के तकाजे का अध्ययन किया है, देश के प्रायः सभी भागों की यात्रा की है, हर हिस्से के प्रबुद्ध लोगों से बातें की हैं और गहरा चिंतन किया है। इसके साथ ही प्रो० दंडवते वीपी सिंह के इलाहाबाद उपचुनाव अभियान में सतत रूप से सक्रिय रहे हैं। अपने इस सारे अध्ययन चिंतन और वैचारिक सर्वेक्षण से गुजरने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी तक एक दूसरे की जड़ खोदते रहे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने और संतुष्ट रखने में सर्वाधिक समर्थ व्यक्ति वीपी ही हैं, और इसीलिए संयुक्त विपक्ष यदि अगले आम चुनाव में बहुमत पाता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह सबसे उपयुक्त पात्र होंगे।

प्रो० दंडवते अपना यह निष्कर्ष वैयक्तिक बतकही तौर पर पहले भी व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसे खुलकर रखा ३० जून को अपनी हैदराबाद प्रेस कांफ्रेंस में। चूंकि भावी प्रधानमंत्री के शगूफे ने विपक्षी एकजुटता जैसे आधारभूत लक्ष्य को ही इन दिनों ग्रस लिया है, इसलिए विपक्षी सोच को साफ करने का यही सही समय था। पत्रकारों के सामने भी सबसे फौरी सवाल यही था। इस प्रेस कांफ्रेंस में प्रो० दंडवते ने कहा, "भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में देश का नेतृत्व करने का दायित्व भरोसे के साथ सौंपने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं।" इन्होंने लोगों में बन रही इस धारणा को गलत बताया कि पूर्व जपा प्रमुख चंद्रशेखर वीपी सिंह के विरुद्ध हैं। दंडवते का कहना था, "विरुद्ध होने का सवाल ही नही उठता। दरअसल इस मुद्दे पर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई फैसला ही नहीं लिया है। सच तो यह है कि प्रक्रिया के अनुसार यह बहुमत प्राप्त संसदीय दल का काम है। पार्टी का नेता चुनने का अधिकार उसे ही है। और चंद्रशेखर ने इसी की ओर ध्यान आकृष्ट किया था।"

आनुषंगिक प्रश्नों के उत्तर में प्रोफेसर दंडवते ने मुख्यतः तीन बातें कहीं: (१) हाल के उपचुनावों ने विपक्षी एकता अनिवार्यतः और शीघ्र कायम करने की आवश्यकता जताई है। (२) कांग्रेस से देश ऊब चुका है, इसलिए राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने का समय आ गया है। (३) अगले संसद सत्र में सारे विरोधी दल समवेत स्वर से राजीव सरकार से इस्तीफा देने और अविलंब आम चुनाव कराने की मांग करेंगे।

चंद्रशेखर की जिस टिप्पणी से विपक्ष में विभ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उसे स्वयं वीपी सिंह चिंताजनक नहीं मानते। ३० जून को बंबई में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "चंद्रशेखर मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह मसला दिल्ली में हम मिलकर हल कर लेंगे।" अगले दिन पटना में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह प्रधानमंत्री का पद मंजूर नहीं करेंगे।

इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने संघीय पार्टी का मसौदा विचार के लिए विरोधी दलों के पास भेज दिया है।

—रंजना कक्कड़

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

अफगान और हमारे हित

कोई आठ वर्ष की कशमकश के बाद सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान से हटनी शुरू हो गयी हैं। जेनेवा समझौते के अंतर्गत अगले वर्ष तक वे पूर्णतया वापस चली जायेंगी पाकिस्तान के शासकों ने शोर शराबा तो बहुत किया था, किंतु अंत में उनको भला इसी में नजर आया कि हस्तक्षेप की नीति को छोड़ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये जायें।

जब से अफगमनिस्तान में इस नये युग का सूत्रपात हुआ है, हमारे यहां भी एक नयी प्रकार की चर्चा चल पड़ी है। कुछ बुद्धिजीवी तथा विदेश नीति के विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि भारत को तो अफगानिस्तान के मामलों में अब न केवल निष्पक्ष ही रहना चाहिए, वरन वहां के शासकों को छूना भी नहीं चाहिए। क्योंकि न जाने इस गृह युद्ध में किसका पलड़ा भारी हो। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान की भी तो यही रट है। उसका कहना है कि पिछले आठ वर्षों की चुप्पी ने भारत को असंगत कर दिया है तथा अब इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वह अफगानिस्तान के संबंधों में अपनी जबान खोले।

ऐसी दलीलें हर प्रकार से थोथी हैं। पहली बात तो यह कि हमारा अफगानिस्तान से क्या और कैसा संबंध हो ? यह अफगानिस्तान तथा भारत के आपसी संबंधों पर निर्भर है, न कि पाकिस्तान के वीटो पर। बहरहाल अब कुछ दिनों से इस्लामाबाद ने इस बात पर जोर देना कम कर दिया है।

दूसरे, अफगानिस्तान हर प्रकार से हमारा पड़ोसी देश है। यदि आज चितराल, गिलगिट तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर पाकिस्तान का गैर-कानूनी अधिकार न होता, तो यह पडोसीपन और उजागर होता।

तीसरे, बंटवारे के बावजूद पाकिस्तान और भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताएं बदली नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदूकुश पर्वत के पास के क्षेत्रों में जो भी घटित होता है, उसका देर-सबेर हमारे महाद्वीप पर प्रभाव पड़ता है।

चौथी तथा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आठ वर्षों के दौरान भी जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में मोरचाबंद थीं, तब दिल्ली ने कभी भी उनके इस हस्तक्षेप को पसंद नहीं किया। इसका हमने समय-समय पर क्रेमलिन से इजहार भी किया है।

भारतीय रुख : दिसंबर १९७९ के अंत में जब मास्को ने आमू नदी के इस पार अपनी सेनाएं उतारने का निर्णय किया, तो हमारी आंतरिक राजनीति एक विचित्र प्रकार के सकट काल से गुजर रही थी। जनता पार्टी का आंतरिक ढांचा बिखर चुका था। चौधरी चरण सिंह की सरकार की कोई साख नहीं जमी थी। चुनाव का दौर शुरू हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में हर पार्टी की दृष्टि विदेश से हटकर आंतरिक राजनीति पर जमी हुई थी। फिर भी चुनावी गरमागरमी के बावजूद प्रधानमंत्री चरण सिह अपना चुनाव अभियान छोड़कर चन्द घंटों के लिए केवल रूसी राजदूत को यह कहने के लिए दिल्ली आये कि भारत इस हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है तथा मांग करता है कि रूसी सेनाएं वापस स्वदेश लौट जायें।

नयी अफगान पीढ़ी को कठमुल्लापन पसंद नहीं

यह दूसरी बात है कि मास्को ने इस विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तो इसलिए कि महाशक्तियां अपनी ताकत के घमण्ड में इस प्रकार के विरोध पर ध्यान कम देती हैं। दूसरे, वहां के नीति-निर्माताओं को यह तो अनुमान होगा ही कि ऐसी आपत्तियां हमारे यहां से आयेंगी। तीसरी, उनकी समझदारी थी कि यदि बात करनी होगी, तो चुनाव के बाद सत्ता में आयी सरकार से करेंगे। तब तक उनके पांव अफगान धरती में भी थोड़ा मजबूती से जम चुके होंगे।

चुनाव में इंदिराजी की जीत हुई। वह पुनः भारत की विदेश नीति की मुखिया बन गयीं। शुरू के कुछ दिनों तक तो दिल्ली में थोड़ा अस्पष्ट वातावरण रहा। नयी प्रधानमंत्री के आसपास ऐसे लोगों का जमघट था जो यह मानकर चले थे कि पूर्व सरकार की जो भी नीति थी, उसे उलट ही देना चाहिए। जल्दबाजी में न तो कोई आंतरिक चर्चा हुई, न देश के हितों का ठीक से विश्लेषण किया गया। एक सक्रिय सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र स्थित हमारे राजदूत ब्रजेश मिश्र को आदेश दे दिया कि वह सोवियत संघ के इस हस्तक्षेप की सराहना करें तथा उसके पक्ष में अपना मत दें।

इस समाचार ने मास्को को तो प्रसन्न कर दिया, किंतु वहीं मौजूद मुझे यह कुछ विचित्र-सा लगा। लेकिन बदले राजनीतिक वातावरण में विश्वास नहीं था कि दिल्ली के नये शासक मेरी बात को किस रोशनी में देखेंगे।

लेकिन यह उलझन बहुत दिन नहीं रही। दो चार दिनों में ही इस गलती का अहसास हो गया। यह नहीं कि इंदिराजी की सरकार क्रेमलिन के साथ मित्रता को किसी प्रकार कमजोर करना चाहती थी। लेकिन उसे अपनी नीति का अनुमान तो लगाना ही था। इसलिए थोड़े ही दिनों में हमने अपनी सोच को सीधा कर लिया। हमारा यह कहना ठीक था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण दो-तरफा है। एक तो सीधा और साफ सोवियत संघ की तरफ से। दूसरा अमरीकी पाकिस्तानी गठजोड़ जो मुजाहिदीन की जोड़ की आड़ लेकर अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। हमारे विचार से ये दोनों बातें गलत थीं।

उस महत्वपूर्ण दिन जब रूसी सेनाएं अपनी सीमा पार कर रही थीं, कामेकान भवन (मास्को) में एक विशाल राजनीतिक स्वागत समारोह हो रहा था। सोवियत संघ के उप-विदेश मंत्री फिरोवियन जो सदा मेरी ओर विशेष ध्यान देते थे, का उत्साह उस दिन सामान्य से कुछ अधिक था। बड़ी देर तक वह विश्व की स्थिति पर चर्चा करते रहे। ईरान उनके ध्यान का प्रमुख केन्द्र था, क्योंकि खुमैनी की नयी सरकार ने अमरीकियों को न केवल चोट दी थी, बल्कि उनके दूतावास के अधिकारियों को भी बंदी बना लिया था। फिरोवियन अपने ढंग से मुझे उसकी ऊंच-नीच बताते रहे। उन्होंने कहा तो नहीं, किंतु बातों से स्पष्ट था कि रूसी विदेश नीति को बड़ी सीमा तक यह खतरा है कि शायद अमरीका इस

अपमान का बदला लेने के लिए ईरान की धरती पर अपनी सेनाएं उतार दे।

उनका यह विश्वास इस बात में पक्का होता था कि अमरीका ने खाड़ी में अपनी सेनाओं को चौकस कर दिया था तथा उनका समुद्री बेड़ा उस ओर मुड़ रहा था। कुछ ही दिनों पहले नाटो ने इस बात का ऐलान भी किया था कि वह तुर्की को नये हथियारों से लैस करेगा। यह सब कुछ सोवियत संघ के द्वार पर हो रहा था। फिरोवियन इन हालात पर चर्चा करते रहे। उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तानी षड्यंत्र की बात तो अवश्य की, किंतु इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं।

अगले दिन बीबीसी के समाचारों ने मुझे चौंका दिया। कुछ हद तक बुरा भी लगा कि हमारे संबंधों के बावजूद मास्को ने हमें पहले से कुछ नही बताया। लेकिन विदेशी मामलों और नीतियों में भावनाओं का स्थान कम होता है।

उस दिन दोपहर को मुझे फिरोवियन ने बुला भेजा तथा विस्तार से बताया कि उनकी मजबूरियां क्या थीं। लेकिन उसमें कोई नयी बात नहीं थी। उन्होंने यह तो मुझे बता दिया कि उनके राजदूत ने दिल्ली में भी यही बात कही है। लेकिन उन्होंने अपना लाभ इसी में समझा कि मुझे यह न बतायें कि जवाब में प्रधानमंत्री (श्रीमती गाँधी) ने क्या कहा था। केवल इतना ही कहा कि वह आशा करते हैं कि भारत इन हालात को मित्रता की दृष्टि से देखेगा। इस बैठक से वापस आने तक तो दिल्ली से भी तार आ चुका था कि वहां क्या बातचीत हुई थी।

कूटनीति: इंदिराजी की सत्ता में वापसी के कुछ ही दिनों बाद सोवियत विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको दिल्ली आये। मास्को की राजनीति में उनका ऊंचा स्थान था। मंत्री होने के अतिरिक्त वह पोलित ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य भी थे। वैसे भी विश्व राजनीति में उनका विशिष्ट स्थान था। इंदिराजी के साथ उनकी निजी बातचीत में सोवियत राजदूत के अतिरिक्त मैं तथा श्री नरसिम्हा राव मौजूद थे। लगभग दो घंटे तक श्री ग्रोमिको इंदिराजी को अफगानिस्तान में हुई घटनाओं का ब्यौरा देते रहे। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह अमरीका व पाकिस्तान मिल कर अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं तथा किन परिस्थितियों ने सोवियत संघ को अपनी सेनाएं भेजने पर विवश किया। इंदिराजी उनकी बातें चुपचाप ध्यान से सुनती रहीं। अंत में उन्होंने गिनेचुने शब्दों में उत्तर दिया—"मैं आपके इस हस्तक्षेप की सराहना नहीं कर सकती।" ग्रोमिको साहब के साथ मेरा पुराना संबंध था। मैंने मास्को में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उनको कभी इस तरह व्याकुल नहीं देखा था जैसा कि वह उस समय थे। इंदिराजी के इस स्पष्ट उत्तर के बाद उनके पास कुछ कहने को नहीं रह गया था। बात समाप्त हो गयी। अगले दिन सुबह ही उनको वापस चला जाना था।

शाम को मुझे सोवियत संघ के राजदूत श्री वारेनसोव ने फोन पर कहा कि वह थोड़ी देर के लिए मुझसे तत्काल मिलना चाहते हैं। मैंने फोन पर ही कारण पूछा। लेकिन वह मिल कर ही बात करना चाहते थे। उन्होंने आकर बताया कि श्री ग्रोमिको को मास्को से श्री ब्रेझनेव ने फोन पर कुछ नये आदेश दिये हैं, जिन्हें वह प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि श्री ग्रोमिको तो अगली सुबह को जाने वाले हैं और इतनी शाम गये मैं प्रधानमंत्री तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, कहना मुश्किल था। राजदूत महोदय कहने लगे कि ग्रोमिको के जाने का समय बदला जा सकता है।

अगले दिन प्रातः फिर से भेंट हुई। इंदिराजी ने तब तक अपना निवास स्थान वापस सफदरजंग रोड पर बदला नहीं था। उनके छोटे से कमरे में श्री ग्रोमिको ने एक नया जाल फेंका। लेकिन इंदिराजी भी राजनीति की चतुर खिलाड़ी थीं। उन्होंने हां या न कहे बिना ही उनकी बात को टाल दिया। अब ग्रोमिको साहब को स्पष्ट था कि अफगानिस्तान के बारे में भारत की नीति मजबूत आधार पर टिकी है।

आज के अफगानी शासक यदि भारत के साथ मित्रता का नाता रखना चाहते हैं, तो यह न तो समझदारी की बात होगी और न ही दूरदृष्टि की कि हम उनसे संबंध इसलिए कमजोर कर लें कि उनके विरोधी कहीं बुरा न मान जायें। रूसी सेनाएं हटने के बाद न केवल दिल्ली तथा मास्को के हित अफगानिस्तान में मेल खाते हैं, बल्कि अमरीका भी दोराहे पर आ खड़ा हुआ है। अमरीका बेशक नहीं चाहेगा कि काबुल में मास्को की कोई कठपुतली सरकार बैठी रहे।

श्री ग्रोमिको की वापसी के बाद मैं कुछ दिनों तक दिल्ली में रुका रहा। विस्तार से जो बातचीत हुई, उसमें हमारी यह नीति बिलकुल स्पष्ट थी कि जहां हम सोवियत हस्तक्षेप को पसंद नहीं कर रहे थे, वहीं हमें अमरीका और पाकिस्तान की सांठगांठ भी सचेत कर रही थी।

श्री ग्रोमिको तो खैर दिल्ली कुछ दिनों बाद आये थे। किन्तु इंदिराजी ने सत्ता में आने के तुरंत बाद ही यह कोशिश शुरू कर दी थी कि जनरल जिया की सरकार के साथ सीधी बातचीत करके इस बढ़ते हुए नये खतरे से निपटने के लिए साझी नीति बनायी जाये। श्री शंकर उस समय इस्लामाबाद में हमारे राजदूत थे। उन्होंने अपने स्तर पर तो बातचीत शुरू भी कर दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली को परामर्श दिया कि एक उच्च स्तर का व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री का विशेष दूत बनाकर इस्लामाबाद भेजा जाये, तो शायद बात आगे बढ़ सके। इसी सलाह पर सरदार स्वर्ण सिंह को वहां भेजा गया। सरदार साहब की पहले जनरल जिया से लंबी बातचीत हुई और बाद में पाक विदेश मंत्री के साथ। दोनों पाक नेता यह मान रहे थे कि इस नये वातावरण ने न केवल अफगानिस्तान, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए नये खतरे पैदा कर दिये हैं। भारत इस सीमा तक भी जाने को तैयार था कि यदि इस्लामाबाद भारत की सीमा से सेनाएं हटा कर उन्हें अपने उत्तर की ओर ले जाना चाहे, तो हम इस बात की गारंटी दुनिया की बड़ी शक्तियों के सामने भी दे सकते हैं कि इस संकट काल का हम कोई लाभ नहीं उठायेंगे और पाकिस्तान के एकीकरण को सुनिश्चित रखेंगे। लेकिन जनरल जिया की आंखें तो वाशिंगटन की ओर लगी हुई थीं, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक जीवन उस समय आंतरिक रूप से डांवाडोल हो रहा था।

जिस समय दिल्ली तथा इस्लामाबाद में इस तरह की बातचीत शुरू हुई और थोड़े दिनों के लिए लगने लगा कि शायद दोनों देश किसी साझा बात पर पहुंच जायें, उसी समय मास्को में परेशानी के कुछ संकेत दिखायी दिये। एक दिन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के साधारण स्तर के एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि वह मुझसे मिलकर बात करना चाहते हैं। मुलाकात होने पर कुछ देर इधर-उधर बातें करने के बाद वह कहने लगे, "हम लोग अपनी इच्छा के विपरीत अफगानिस्तान के अंदर खिंच गये हैं। हम नहीं चाहते कि वहां हम बैठे रहें। यद्यपि यह हमारी इच्छा और आवश्यकता अवश्य है कि अफगानिस्तान में स्थिर तथा मित्रतापूर्ण शासन हो। अपने सम्पूर्ण इतिहास में हमने तो कभी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया—न ही समाजवादी क्रांति से पहले और न ही बाद में। यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व की अंग्रेजी सरकार से अफगानिस्तान के विरुद्ध पिछली एक शताब्दी में तीन लड़ाइयां लड़ी हैं तथा वहां प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की है। हमारी मित्रता तो शाह और राष्ट्रपति दाऊद के साथ बराबर की थी। पाकिस्तान और अमरीका के हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र से हमारा प्रभाव समाप्त करने की कोशिश की है।" इस अंदाज से वह लंबी बात करने के बाद मुद्दे पर आये। कहने लगे कि यह बातचीत तो आप और मुझमें निजी स्तर पर हुई है। लेकिन अगले कुछ दिनों में पार्टी का एक उच्च स्तर का व्यक्ति आपसे बात करेगा। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा ईरान के नेता खुमैनी मिलकर इस समस्या को सुलझा दें।

अब मेरे भी कान खड़े हुए। मैंने उनके मन को टटोलना शुरू किया तथा बातचीत का सिलसिला तीन बैठकों में जारी रहा। यद्यपि उन्होंने तो कहा था कि यह बात फिलहाल मैं अपने तक ही सीमित रखूं। लेकिन राजदूतों के लिए यह काम जोखिम का होता है। मैंने दिल्ली को सूचित किया, तो यहां से उत्तर आया कि बात को बढ़ाया जाये।

मास्को का प्रस्ताव : अब यह अनौपचारिक बता जरा ठोस रूप लेने लगी। उनका कहना था कि हमारे (भारत के) तथा ईरान के हस्तक्षेप से सबको लाभ होगा। मैंने पूछा कि हमारा तो अफगानिस्तान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। भला वहां हमारी बात कोई क्यों सुनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगी सीमा डूरण्ड रेखा को आज तक न तो अफगानिस्तान ने मान्यता दी है और न ही मास्को ने। पाकिस्तान को यह लाभ होगा कि इस प्रकार की बातचीत से वह अपनी सीमा को वैधानिक मान्यता दिलवा सकेगा और पखतूनिस्तान की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। इसी तरह यदि निर्णय भारत की सहायता से होगा, तो कश्मीर की सीमा निर्धारण का अंतिम निर्णय भी किया जा सकता है। पाकिस्तान एक मात्र देश है, जिसकी आज दोनों सीमाएं कोई वैधानिक मान्यताएं नहीं रखतीं। इस में भारत का भी लाभ इस प्रकार होगा कि कश्मीर की समस्या हल हो जायेगी।

मैंने प्रश्न किया कि इसमें आप इमाम खुमैनी को क्यों घसीटने की राय दे रहे हैं। उनका उत्तर था कि वैसे तो ईरान की रुचि अफगानिस्तान में सदा ही रही है तथा अब भी उसका ध्यान बंटा नहीं है। खुमैनी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने से दक्षिण एशिया में एक नये प्रकार की स्थिरता आयेगी तथा अमरीकियों का प्रभाव समाप्त होगा। बात वाजिब थी।

लेकिन विदेशी राजनीति तो हालात के अनुसार अपने को ढालती है। इधर मास्को के यह वरिष्ठ व्यक्ति मुझसे इस प्रकार की अनौपचारिक बात कर रहे थे, उधर दिल्ली से आयी सूचनाओं से पता चल रहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत कोई गंभीर रंगत नहीं ले रही है। जैसे ही सूचना आयी कि अमरीका ने पाकिस्तान को पुरस्कारस्वरूप हथियारों की बहुत बड़ी सहायता देना मजूर कर लिया है, तो हमारी बातचीत मास्को में भी ठंडी पड़ गयी तथा उसके बाद कभी इसका जिक्र भी नहीं आया।

दरअसल ऐसा लगता है कि निचले स्तर की यह बातचीत एक प्रकार से यह टटोलने के लिए की गयी थी कि यदि कभी भारत तथा पाकिस्तान में कोई परस्पर समझौता हो जाये, तो सोवियत संघ को क्या करना होगा। लेकिन वह हुआ ही नहीं। मैं आज भी समझता हूं कि यदि पाकिस्तान में कोई दूरंदेश सरकार होती, तो इस समस्त क्षेत्र की राजनीति अलग़ होती। एक प्रकार से अमरीकी सरकार ने भी अवसर गंवा दिया। उसकी नीति ने अफगानिस्तान के नाम पर बजाय दक्षिण एशिया को एकजुट करने के, यहां तनाव बढ़ा दिये।

पिछली बात पर आते हुए—मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि बीते वर्षों में एक भी अवसर या समय ऐसा नहीं था, जब भारत ने सोवियत संघ, पाकिस्तान तथा अमरीका के हस्तक्षेप पर आपत्ति न की हो। भारत के नेताओं ने जब भी सोवियत नेताओं से बात की, सदा इस पर जोर दिया कि उनकी सेनाओं की वहां से जल्द वापसी होनी चाहिए। आपसी बातचीत तथा दूसरे देशों के अधिकारियों से वार्तालाप में भी दिल्ली ने अपनी स्थिति की अभिव्यक्ति सफाई से की। यह दूसरी बात है कि हमने न तो अमरीकी गुटबंदी का भाग बनकर सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया तथा न ही उनके विरोध में कोई मोर्चा खड़ा किया। हमारे अपने हित इस बात की अनुमति नहीं देते थे। यदि पाकिस्तान को अमरीका से आधुनिक हथियार लेने थे, तो हम मास्को के साथ अपने रिश्तों में कडवांहट नहीं डाल सकते थे।

विदेश नीतियां न तो नैतिक बातों और न ही सैद्धांतिक स्वप्नों से निर्धारित होती हैं। इनको बनाने में तो तात्कालिक तथा दूरगामी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होता है। इसीलिए हमारा काम जरा टेढ़ा था। रूसी सेनाओं का अफगानिस्तान में आना तो हमें मान्य नहीं था, किंतु उनके साथ अपने पुराने तथा स्थायी संबंधों को कमजोर करने से हमारी सुरक्षा को खतरा था।

बीते वर्षों में एक भी अवसर या समय ऐसा नहीं था, जब भारत ने सोवियत संघ, पाकिस्तान तथा अमरीका के हस्त क्षेप पर आपत्ति न की हो। भारत के नेताओं ने जब भी सोवियत नेताओं से बात की, सदा इस पर जोर दिया कि उनकी सेनाओं की वहां से जल्द वापसी होनी चाहिए। आपसी बातचीत तथा दूसरे देशों के अधिकारियों से वार्तालाप में भी दिल्ली ने अपनी स्थिति की अभिव्यक्ति सफाई से की।

१९८२ में मैं काबुल गया था। स्पष्ट था कि इस नये संकट में वहां के हालात में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि ब्रेझनेव की मृत्यु की सूचना मिली। दरअसल यह समाचार हमारे छोटे से ग्रुप को बबरक करमाल ही ने दिया। इस समाचार का काबुल की सामान्य जनता के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न तो कारोबार बंद हुए तथा न कोई बड़ी शोक सभा ही हुई। राजनीतिक नेताओं ने अपने कर्तव्य अवश्य निभा दिये।

अफगानिस्तान की मनोदशा : क्रान्ति और दोतरफा हमले ने अफगानिस्तान का चेहरा तथा सोच को बदल दिया था। यद्यपि सुदूर गांव में रहने वालों की मनोदशा बड़ी सीमा तक प्राचीन कबीलों से बंधी रही। लेकिन शहरों और नगरों में एक नया प्रतिष्ठित वर्ग उभर आया था जो सुशिक्षित तथा आधुनिक युग के साथ अपना नाता भी जोड़े हुए है। रूसी प्रभाव के बीच युवा पीढ़ी के हजारों लड़के-लड़कियां समाजवादी देशों में पढ़ आये हैं अथवा कोई-न-कोई प्रशिक्षण ले आये हैं; इससे वहां के मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। स्पष्ट है कि बाकी जगहों की तरह इनमें से कुछ सोवियत नीतियों की सराहना करते थे तथा कुछ निन्दा। अधिकांश ऐसे भी थे जो राजनीत्तिक मामलों पर राय न देने में हीं भलाई समझते थे। लेकिन आज की स्थिति पर राय बनाते समय हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता में रचा-बसा अफगान मध्यम वर्ग उन समस्त शक्तियों के विरुद्ध रहेगा जो उनको पीछे की ओर ले जाती हों।

उसी दौरान मैं अपने पुराने मित्र राजदूत अली अहमद पोपली से भी मिला। वह शाह और दाऊद के समय बहुत से देशों में राजदूत रह चुके थे तथा इससे पहले वह काबुल में शिक्षा मंत्री थे। क्रान्ति के समय वह मास्को में थे, जहां हम अकसर मिला करते थे। लेकिन नयी सरकार के साथ न तो उनकी मित्रता थी और न ही सहानुभूति। कठिनाई से मुझे उनका पता मिला। अपने छोटे से घर में किताबों से घिरे हुए श्री पोपली गुमनामी का जीवन बिता रहे थे। बात करने में पहले तो वह झिझके, लेकिन जल्दी ही खुल गये। उनको बहुत शिकायत थी कि इस कठिन समय में हमने (भारत सरकार ने) खुल कर उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा था, "आप की कठिनाइयों के समय जब कभी हमको भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव का मौका आया, तो हमने सदा आप ही का हाथ पकड़ा। अब पुराना विरोधी तो हमारा साथ दे रहा है और आप पल्ला छुड़ा रहे हैं।"

बात अभी चली ही थी कि उनके एक पुराने मित्र प्रोफेसर मोहम्मद अनवर अरगादेवाल भी वहां आ गये। एक समय वह भी अफगान सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। हालात के विपरीत दोनों एक मत थे। उनको इंदिराजी की नीतियों पर तो विशेष आपत्ति थी। उनका कहना था कि हमारी प्रधानमंत्री विभिन्न लोगों और देशों को विभिन्न बातें कहती हैं।

मैंने उनको अपनी मजबूरियां समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका कहना था कि ये सब बातें एक साधारण अफगानी के लिए बहुत उलझी हुई हैं और एक देशभक्त तो आज केवल यह देखता है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन नहीं।

उनकी स्पष्टवादिता मुझे पसंद थी और यह शिकायत और शिकवा भी तो एक दोस्त का था, जिसके दिल और भावनाओं को गहरी चोट लगी थी। उनकी दो बातें मुख्य थीं। पहली बात उन्होंने कही, "ध्यान रखिए, इतिहास का यह पाठ है कि जो आज यहां हो रहा है, वह ही कल आप के यहां होने वाला है।" और दूसरे, "हम अफगानी मूल रूप में क्रान्तिकारी हैं। हमारी क्रान्तिकारी मित्रता का रंगरूप बबरक करमाल छाप नहीं, बल्कि स्वाभाविक

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत
ASPRO
draws out pain faster
सरदर्द का
बेहतरीन
उपचार
दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा
daCunha/AS/41/87 HIN

तथ

सम
वर्गी
विश
अफ
बाते
विश
डाक
उन्हे
आप
अंग
उन
रहे
थे ज
कब
तोड़

करे
कि
साम
पहले
इन
करे

जाते
को
भाग
संम
तथा

की
पर
आव
भाग
में तं
में इ
इनवे
इनमें
पानि
बात

सम
भी
दिने
से व
बलू
आ

अफ
रखत
है, ले
उन
मौज
अफ

तथा बुनियादी है। हम आधुनिकता पसंद लोग हैं।"

आज की अफगानिस्तान की समस्या को समझने के लिए यही दो बातें कुंजी हैं। ये दोनों उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सोवियत संघ के तो विरुद्ध हैं, किंतु आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं। अफगानी समाज के दो और प्रतिनिधियों से भी मेरी बातें हुई थीं। प्रोफेसर उमर फ्रांस के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। उनकी पत्नी यूरोप में डाक्टरी पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। उन्हें रूसी सेनाओं के आगमन पर कोई बुनियादी आपत्ति नही थी। वह इसे सउर क्रांति का अभिन्न अंग मानते थे, क्योंकि पाकिस्तान तथा अमरीका उनकी क्रांति को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह उसी प्रतिष्ठित वर्ग का एक भाग थे जो आपसी विभाजन के बावजूद पुराने रूढ़िवादी कबाइली रीतिरिवाज तथा सोच से अपना रिश्ता तोड़ चुके थे।

इन दोनों विपरीत समुदायों के बारे में जिक्र करने से मेरा तात्पर्य यह है कि जो लोग यह सोचते हैं कि रूसी सेनाओं के हटने के बाद उस देश में सामाजिक वातरवरण वैसा ही हो जायेगा जैसा पहले था या दूसरे अफगान युद्ध के बाद था, तो वह इन बुनियादी सामाजिक परिवर्तनों को अनदेखा करते हैं।

हमारे यहां ऐसे बुद्धिजीवी यह बात भी भूल जाते हैं कि इस लम्बे संकट काल ने अफगान समाज को केवल सोवियत मित्र तथा सोवियत शत्रु जैसे भागों में नहीं बांटा, बल्कि इससे आगे बढ़ कर समस्त रहन-सहन तथा सोच में कई नयी उलझनें तथा कई नये आयाम उभारे हैं।

विभाजित मुजाहिदीन : बागी मुजाहिदीनों की सहायता करने से पाकिस्तान का प्रभाव इस वर्ग पर तो अवश्य बढ़ा है, लेकिन यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि मुजाहिदीन आपस में आठ-दस भागों में बंटे हुए हैं। सोवियत संघ का विरोध करने में तो यह आपस में गठजोड़ कर सकते थे, किंतु बाद में इनके एकजुट रहने की आशा नहीं है। न केवल इनके कबीले अलग हैं, बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी इनमें काफी मतभेद है। दूसरे, कठिन समय में पाकिस्तान के रास्ते अमरीकी सहायता लेना एक बात थी, उसका पिट्ठू बनना बिलकुल दूसरी बात है।

यहा यह कहना भी उचित होगा कि इस समस्त अवधि में मुजाहिदीनों के किसी समुदाय ने भी डूरेण्ड रेखा को मान्यता नहीं दी है। आगामी दिनों में यदि पाकिस्तान के शासकों ने सूझबूझ से काम न लिया, तो पखतूनिस्तान तथा आजाद बलूचिस्तान का नारा फिर से उभर कर सामने आ सकता है।

आज के वातावरण में हम प्रायः अफगानिस्तान के दूसरे पड़ोसी ईरान का ध्यान कम रखते हैं। आज तेहरान इराक के साथ उलझा हुआ है, लेकिन उसके हित अफगानिस्तान में स्थायी हैं। उनके यहां भी एक बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी मौजूद हैं जिनको उसे वापस भेजना है। यदि अफगानिस्तान में रूढ़िवादिता का ही वातावरण बनता है, तो ईरान की शिया रूढ़िवादिता का अपना रंगरूप है जो पाकिस्तान की सुन्नी रूढ़िवादिता से टकरा सकती है।

चींन की सीमा भी तो अफगानिस्तान से मिलती है। आठ वर्ष पहले तो उन्होंने भी सोवियत संघ के विरुद्ध आवाज उठायी थी। लेकिन बाद में यह धीमी पड़ गयी। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उनकी रुचि कम हो गयी है। अफगानिस्तान में गृह युद्ध जोर पकड़ गया, तो चीन भी उसमें कूद सकता है।

कुल मिलाकर अफगानिस्तान का भविष्य चिन्ताजनक है तथा उसकी खीचातानी कई तरफ से हो सकती है। इन हालात में केवल भोले लोग ही यह सलाह दे सकते हैं कि भारत किनारे खड़ा केवल नजारा देखता रहे। अफगानिस्तान की आंतरिक अस्थिरता उसकी भीतरी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह पायेगी। यह लावा उसी तरफ बह निकलेगा जहां उसको जमीन कमजोर नजर आयेगी। पश्चिमी एशिया इस समय ऐसा ही लगता है। विशेषकर तब जब जनरल जिया आग से खेलना अपना एक शौक समझते रहे हैं। जेनेवा समझौते पर मुहर लगाने के बाद भी वह अपनी नीयत को संभाल नहीं पाये। इसीलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जुनेजो को भी चलता कर दिया है। पाकिस्तान की जनता तथा विपक्ष तो जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि इस खेल को बन्द करो और तीस लाख से भी अधिक अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की तरकीबें सोंचो। लेकिन जिया साहब यह स्वप्न देख रहे हैं कि अफगानिस्तान शायद उनके प्रभाव क्षेत्र में वैसे ही आ जायेगा जैसाकि एक समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ था।

हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया था। बाद में राजीव गांधी उनसे न्यूयार्क में भी मिले हैं। यह न तो अनोखी बात है, न नयी बात है। इस संकट काल में भी हमारा राजदूत काबुल में बरकरार रहा है तथा उनके यहां जितने भी राज बदले हैं, हमने उनको मान्यता दी है। पाकिस्तान ने भी यही किया है, लेकिन जरा आंख बचाकर। उसने राजदूत तो वापस बुला लिया, लेकिन दूतावास के बाकी कर्मचारी तथा कार्यदूत वहां बने रहे तथा सरकार से रिश्ता बनाये रखा। इसी तरह अफगानिस्तान का दूतावास भी इस्लामाबाद में कारोबार करता रहा। तो फिर जिस सरकार को हम मान्यता देते हैं उसके प्रधान को बुलाकर हम उनको कोई निजी मान्यता थोड़े ही दे रहे थे। यह रिश्ते व्यक्तियों से नहीं, सरकारों से होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नजीबुल्ला को परामर्श दिया है कि बदले हुए वातावरण में अपनी सरकार का विस्तार करें, ताकि दूसरे समुदाय तथा विपक्ष वाले भी उसमें शामिल हो सकें और समझौते का वातावरण बने।

आज के अफगानी शासक यदि भारत के साथ मित्रता का नाता रखना चाहते हैं, तो यह न तो समझदारी की बात होगी और न ही दूरदृष्टि की कि हम उनसे संबंध इसलिए कमजोर कर लें कि उनके विरोधी कहीं बुरा न मान जायें। रूसी सेनाएं हटने के बाद न केवल दिल्ली तथा मास्को के हित अफगानिस्तान में मेल खाते हैं, बल्कि अमरीका भी दोराहे पर आ खड़ा हुआ है। अमरीका बेशक नहीं चाहेगा कि काबूल में मास्को की कोई कठपुतली सरकार बैठी रहे। लेकिन शायद वहां की रूढ़िवादी सरकार भी तो उसे मंजूर नहीं होगी। क्योंकि उसने ईरान तथा अन्य स्थानों पर देखा है कि इस प्रकार के रूढ़िवादी बहुत दिनों तक उसका साथ नहीं दे पाते और यदि इसी प्रकार की सरकारें ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में सत्तारूढ़ हो जायें, तो हम तीनों के हितों पर चोट पहुंचती है।

मौजूदा हालात में जबकि जनरल जिया तथा उनके कुछ मुजाहिदीन दोस्त अफगानिस्तान में फिर से लड़ाई और तनाव का माहौल बना रहे हैं, हमारे सामने बहुत कम रास्ते रह जाते हैं।

यद्यपि सोवियत संघ अपनी सेनाएं तो हटा रहा है, लेकिन मुजाहिदीनों द्वारा कंधार के आसपास किये गये हमलों ने गोर्बाचोव को यह कहने पर विवश किया है कि यदि ऐसी घटनायें जारी रहीं, तो उनको अपनी नीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। न तो पाकिस्तान और न ही अमरीका उनकी इस चेतावनी को एक झटके से रद्द कर सकता है। इस नाजुक स्थिति में हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि तनाव को बढ़ने से रोकें। इसीलिए हमारा इसमें दिलचस्पी लेना और भी आवश्यक हो जाता है।

—इन्द्र कुमार गुजराल

यद्यपि सोवियत संघ अपनी सेनाएं तो हटा रहा है, लेकिन मुजाहिदीनों द्वारा कंधार के आसपास किये गये हमलों ने गोर्बाचोव को यह कहने पर विवश किया है कि यदि ऐसी घटनायें जारी रहीं, तो उनको अपनी नीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। न तो पाकिस्तान और न ही अमरीका उनकी इस चेतावनी को एक झटके से रद्द कर सकता है। इस नाजुक स्थिति में हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि तनाव को बढ़ने से रोकें। इसीलिए हमारा इसमें दिलचस्पी लेना और भी आवश्यक हो जाता है।

शेयरों के लिए कर्ज

यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी हैं और उसके शेयरों को पांच प्रतिशत आरक्षित कोटे के तहत खरीदने के अधिकारी हैं, तो आप शेयरों के खरीद मूल्य का ९० प्रतिशत तक बैंक से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज राशि की सीमा २० हजार रु० या छह का वेतन—इनमें से जो भी कम होगा—वह होगी। यह पहली बार वित्तमंत्री द्वारा संसद में घोषित नयी रियायतों से संभव हुआ है। ब्याज की दर साढ़े १६ प्रतिशत होगी।

बहरहाल, सरकार अभी भी अमरीका में प्रचलित 'सट्टा विकल्प' पर विचार करने को अनिच्छुक लगती है। इस योजना के तहत कंपनी अधिकारियों को—खासकर प्रबंध श्रेणी के बाजार में प्रचलित मूल्य से कम दाम पर कंपनी के कुछ शेयर इस विकल्प पर दिये जाते हैं कि अधिकारी शेयरों का नकदीकरण एक निश्चित समय के बाद मसलन १० से १५ वर्षों में करें। इस प्रकार अधिकारी कंपनी में सामान्यत: बना रहता है, क्योंकि यदि वह उसे छोड़कर जाता है, तो आर्थिक क्षति होती है। भारत में किर्लोस्कर आयल इंजिन्स ने ऐसा प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, किंतु ऐसा लगता है कि सरकार ने वित्तीय संस्थानों की सलाह पर उसे नामंजूर कर दिया है। संस्थानों को संदेह है कि कंपनी प्रबंधक इस छूट के सहारे अपने संबंधियों को लाभ पहुंचायेंगे।

हिंदुजा फिर सुर्खियों में

हिंदुजा फिर सुर्खियों में हैं। पहले बोफोर्स सौदे में कमीशन पाने तथा देश की दूसरे नंबर की ट्रक निर्माण कंपनी अशोक लेलैंड के मालिक बनने पर उनका नाम उछला था। इस बार चर्चा का विषय यह है कि हिंदुजा भाइयों की नजर पुणे स्थित गेस्ट कीन विलियम्स (जी के डब्ल्यू) पर है, तो देश का आधुनिकतम प्रेसिंग प्लांट माना जाता है। जी के डब्ल्यू ने भारी और हलकी व्यावसायिक गाड़ियों के हिस्से बनाने के लिए १५ करोड़ की लागत से चार वर्ष पूर्व यह इकाई लगायी थी। बदकिस्मती से फैक्ट्री ठीक से चल नहीं पायी और शुरू से ही घाटे का सामना करना पड।

आटोमोबाइल (गाड़ी) उद्योग की जानी-मानी कंपनी महिंद्रा भी पुणे की इस इकाई के लिए बोली लगा रही है। पर इन दिनों हिंदुजा की ही तूती बोल रही है। सौदा अंतत: भारत में नहीं लंदन में पटेगा, क्योंकि जे के डब्ल्यू एक फेरा कंपनी है। जिसके ४७ प्रतिशत इक्विटी शेयर ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी जे के डब्ल्यू के पास हैं। फिर हिंदुजा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, हथियार व्यापारियों और उनके संगी साथियों से सौदा करने में माहिर जो हैं।

रिलायंस की चांदी

दो महीने पहले जो शेयर बाजार मंदी का शिकार था, सहसा वह किसी जादू से गहमागहमी से भर उठा है। रिलायंस द्वारा परिचालित अधिकांश-शेयरों का कारोबार जोरों पर है। सट्टा बाजार का सूचकांक १५ अप्रैल और ३ जून के बीच ५० प्रतिशत तक बढ़ गया था। रिलायंस ७५ से २०० अर्थात लगभग तीन गुना बढ़ गया था और टाटा करीब ६०० से ८०० पर पहुंच गया था। अन्य शेयरों में भी बढोत्तरी हुई, गोकि उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी।

इसकी वजह क्या है? कहा जाता है कि वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा लोकसभा अधिवेशन के अंतिम दिन दी गयी नयी रियायतों का यह कमाल है। किंतु इन रियायतों की काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थीं और वे इतनी अधिक प्रभावशाली भी नहीं थीं। आगामी मानसून का शुभ समाचार एक कारण हो सकता है, किंतु उद्योग का कामकाज अच्छे अथवा बुरे मानसून के बावजूद पर्याप्त संतोषजनक था। यह आम धारणा प्रतीत होती है कि बोफोर्स का कांटा निकलने से राजीव सरकार उस शहरी मध्य वर्ग को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हाल की घटनाओं से प्रसन्न नहीं थी।

एस्सोचैम अव्वल

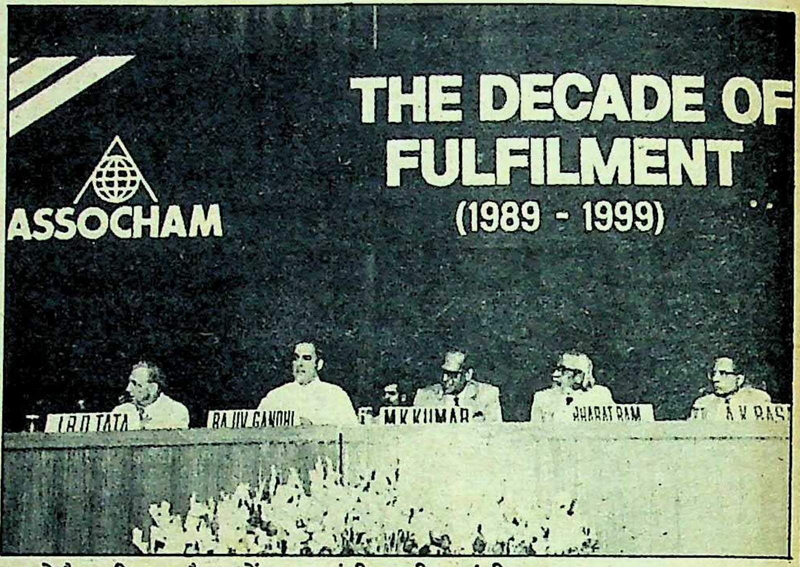

एस्सोचैम की एक बैठक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी

एसोशियेटेड चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एस्सोचैम) ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हाल में दिल्ली के अपने एक अधिवेशन में भाषण देने के लिए राजी करके एक धमाका-सा किया था। एस्सोचैम के वर्तमान अध्यक्ष ललित थापर, जोकि दून स्कूल के प्रशासकीय निकाय के अध्यक्ष भी हैं, कदाचित इसमें मददगार साबित हुए थे। चैंबर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता हुआ अब देश का प्रथम श्रेणी का चैंबर बन कर फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) से बाजी मार ले गया है, जो अब तक सरकार का कृपापात्र था।

किंतु सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि चैंबर को इस अहम् मुकाम पर लाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति खुद अपने पद से हाथ धोने जा रहा है। एस्सोचैम का भाग्योदय एकाउंटेंट अरुण के बसाक के आगमन से प्रारंभ हुआ था, जो सीधे वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक से चैंबर के महानिदेशक पद संभालने आये थे। इसके पूर्व चैंबर के सभी शीर्ष पदाधिकारी मात्र महासचिव पद पर ही शोभित थे।

अंकों की हेराफेरी?

महान आश्चर्य? थोक मूल्य सूचकांक पिछले महीने गिर गया, यद्यपि यह कहावत है कि चढ़ा मूल्य नीचे नहीं उतरता। ऐसा लगता है कि हम इस वर्ष दोहरे अंक की मुद्रास्फीति से करीब-करीब बच गये, गोकि इस बात पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि भयावह दोहरे अंकों से पिंड छुड़ाने के लिए कुछ अंकों में हेरफेर अथवा चंद दशमलव बिंदुओं का प्रबंध करना मुश्किल नहीं।

संयोगवश विश्व का कौन-सा देश मुद्रास्फीति का सर्वाधिक शिकार है? भारत सर्वाधिक कम मुद्रास्फीति वाले देशों में है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में १९८०-८५ के दौरान मुद्रास्फीति की दर ८ प्रतिशत वार्षिक थी। सर्वाधिक मुद्रास्फीति वाला लैटिन अमरीकी देश बोलीविया है, जिसकी दर ५७० प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा ५० प्रतिशत प्रति माह है। यह उसी तरह है जैसे आप किसी महीने एक केला ५० पैसे में खरीदें और चार महीने में उसकी कीमत दो रु० हो जाय। सर्वाधिक मुद्रास्फीति के अन्य देश हैं, अर्जेन्टीना (३४३ प्रतिशत प्रति वर्ष), इस्राइल (१९६) और ब्राजील (१४८)। बोलीविया, अर्जेन्टीना व ब्राजील लैटिन देश हैं, जो उच्च मुद्रास्फीति के वैसे ही माहिर हैं जैसे बढ़ती आबादी के। और न्यूनतम मुद्रास्फीति वाला देश कौन है? आप मानें या न मानें उत्तर है कुवैत, जहां १९८० से १९८५ के बीच मूल्यों में ३.६ प्रतिशत वार्षिक गिरावट आयी।

आकार में तुलना

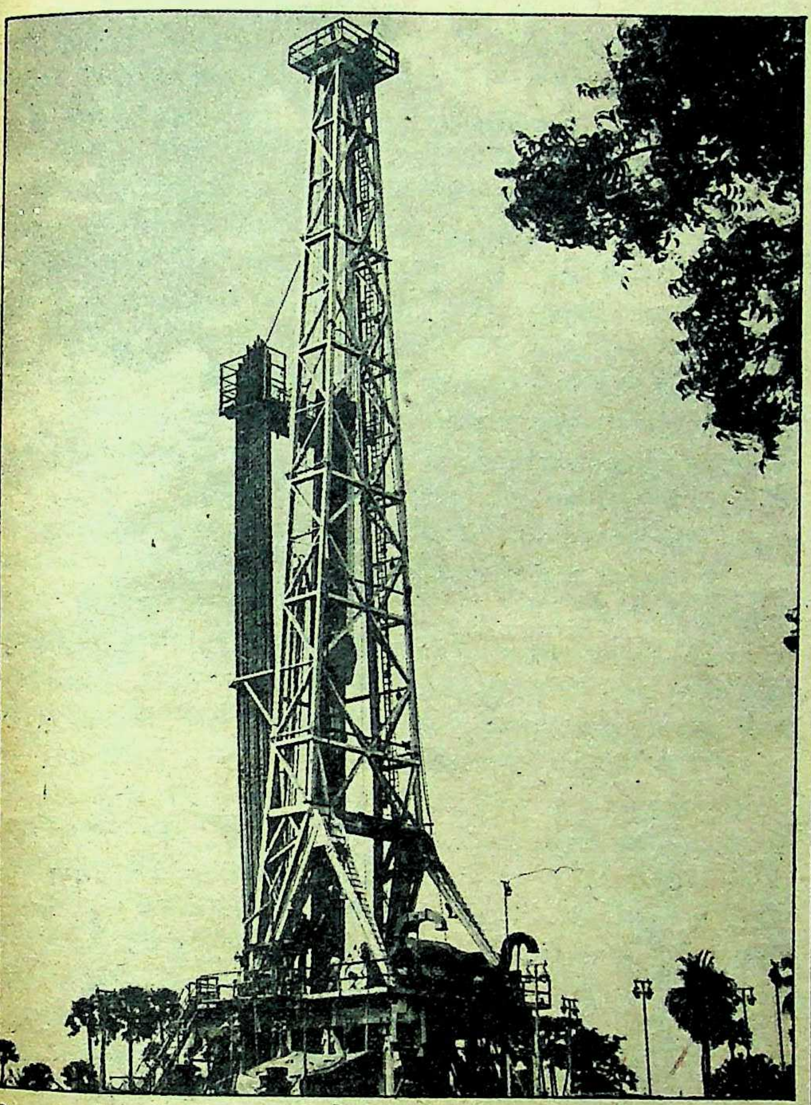

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का एक संयंत्र

आप सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की तुलना उनकी उपलब्धि के रूप में नहीं, आकार के रूप में निजी क्षेत्र से कैसे करेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई तेल व प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, जिसकी परिसंपत्तियां २००२ करोड़ रु० की हैं, से पांच गुना बड़ी है, जबकि ओएनजीसी की परिसंपत्तियां ११६२१ करोड़ की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पांचवीं सबसे बड़ी इकाई भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) निजी क्षेत्र की अपनी समानधर्मी कंपनी सदर्न पेट्रोकेमिकल्स (एसपी) से नौगुना बड़ी है। एफसीआई की परिसंपत्तियां ६३२१ करोड़ रु० की हैं, जबकि एसपी की केवल ७२८ करोड़ की हैं।

दरअसल यदि आप तीन शीर्ष व्यावसायिक समूहों को जोड़ दें, तब कहीं जाकर मुश्किल से वह ओएनजीसी की परिसंपत्तियों का मुकाबला कर सकती हैं। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की पांच शीर्ष कंपनियों—ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया व एफसीआई की कुल परिसंपत्तियों को जोड़ दें, तो वह निजी क्षेत्र के ५० शीर्ष समूहों की मिली-जुली परिसंपत्तियों से ३० प्रतिशत अधिक बैठेगी।

ओएनजीसी अपनी कुल परिसंपत्तियों, कुल लाभ और कर अदायगी के पूर्व लाभांश की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सिरमौर है। कुल बिक्री की दृष्टि से इंडियन आयल्स अव्वल नंबर पर है। उसकी बिक्री ओएनजीसी से दुगुनी है। दरअसल इन पांच इकाइयों—ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया व एफसीआई का सार्वजनिक क्षेत्र में वर्चस्व है और अपनी परिसंपत्तियों, बिक्री और मुनाफे में भी वे आगे हैं।

भीमकाय विदेशी समूह

भारत में सबसे बड़ा विदेशी व्यापारिक समूह कौन है? यह दर्जा यूनियन कार्बाइड को भोपाल की भीषण दुर्घटना के पूर्व तक हासिल था। फिर हिंदुस्तान लीवर को यह स्थान प्राप्त हुआ, गोकि यह उतना विशाल समूह नहीं था। किंतु उसके जनक समूह का यूनिलीवर द्वारा लंदन में अधिग्रहण किये जाने के बाद ब्रुक बांड भी उसके साथ शामिल हो गया। यूनिलीवर कदाचित लंदन और एम्सटर्डम के बाहर कार्यरत सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसने अब अमरीकी प्रसाधन कंपनी चेसेब्रो-पांड्स को खरीद लिया है जिसकी मद्रास स्थित एक भारतीय शाखा पांड्स इंडिया के नाम से कार्यरत है। इसके अलावा लिपटन भी है जो पहले मूलतः चाय-काफी की कंपनी थी, किंतु अब डालडा बनाती है। पहले डालडा हिंदुस्तान लीवर बनाता था, किंतु चार वर्ष पूर्व उसने तथाकथित अल्प तकनीकी व्यापारिक जिन्सों से पिंड छुड़ाने के लिए इसे लिपटन को हस्तांतरित कर दिया था। इस प्रकार भारत में यूनिलीवर समूह के अधीन चार कंपनियां कार्यरत हैं तथा इसकी बंबई स्थित प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान लीवर है।

क्या ये कंपनियां अपने को पुनर्गठित कर अपने व्यावसायिक गतिविधियों को सुसंगत बनायेंगी? इनकी गतिविधियां अधिकांशतः प्रतिद्वंद्वितामूलक हैं। ब्रुक बांड और लिपटन के पास चाय व काफी के बागान हैं और वे चाय-काफी भारी मात्रा में बेचती हैं।

हिंदुस्तान लीवर और पांड्स इंडिया साबुन और प्रसाधन सामग्री बनाती हैं और इनकी अपनी अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं। क्या ये इसी रूप में बरकरार रहेंगी? इस सवाल में ग्राहकों से अधिक दिलचस्पी उनके शेयरधारियों को है।

सरकार का निजीकरण

डा० एएस गांगुली

जिन व्यापारियों से एक समय नयी दिल्ली के राजनीतिज्ञों ने किनाराकशी कर ली थी, वही धीरे-धीरे घुसपैठ करके आज राजनीतिज्ञों को क्या करना चाहिए—यह बता रहे हैं। राजीव गांधी सरकार के असली निर्णय लेनेवाले तंत्र का निजीकरण हो रहा है। निजी उद्योग के महत्वपूर्ण व्यवसायी प्रमुख सलाहकार पदों पर बिठाये जा रहे हैं।

हाल में एक संचालन समिति गठित की गयी है जो सरकार को अगली योजना-आठवीं योजना पर सलाह देगी जिसमें उद्योग का विशेष उल्लेख होगा। इनके ६ में से कम-से-कम ४ सदस्य—मंतोष सोंधी, एएस गांगुली, वीजी राज्याध्यक्ष व रूसी मोदी निजी उद्योग से संबंधित हैं, गोकि मंतोष सोंधी एक समय में सरकार से संबद्ध थे। गांगुली और राज्याध्यक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हैं।

ताज्जुब है कि इनमें बिड़ला अथवा कोई अन्य मारवाड़ी समूह शामिल नहीं, यद्यपि इन समूहों का निजी उद्योग पर वर्चस्व है। दरअसल, उपर्युक्त चारों लोग मालिक नहीं, प्रबंधक हैं। इनमें से दो—सोंधी और राज्याध्यक्ष—पहले सरकार में काम कर चुके हैं। राज्याध्यक्ष हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। सरकार बिड़ला-गोयनका जैसे मालिकों और उनके प्रबंधकों की तुलना में तराशे हुए एक्जिक्यूटिवनुमा लोगों को शायद पसंद करती है।

—जय दुबाशी

लाइसेंस छूट

फायदा किसको ?

"इस उद्योगपति को देखिए जो अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर ही मांगों का एक पुलिदा पेश कर रहा है," यह टिप्पणी तत्कालीन वित्त और वाणिज्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने १०० करोड़ रुपए के पालियस्टर चिप प्लांट के उद्घाटन के मौके पर ईस्टर्न इंडिया के चेयरमैन सीताराम सिंघानिया के भाषण के जवाब में की थी। सिंघानिया ने अपने भाषण में उप्र के नैनीताल के निकट खटीमा में क़ायम अपने नये प्लांट की असंख्य समस्याओं का उल्लेख किया था। मसलन दूरसंचार, बिजली आदि की नाममात्र की उपलब्धता जो पिछड़े क्षेत्रों में एक आम बात है। सिंघानिया ने थोड़ी नाटकीयता का परिचय देते हुए अपनी मांगों की एक नीली पुस्तक तिवारी को भेंट करते हुए मौजूद लोगों से कहा था, "मैं आपकी मौजूदगी में इन्हे यह किताब दे रहा हूं, जिससे (तिवारी) बाद में यह न कहें कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था।"

इस पर तिवारी आगबबूला हो गये। उन्होंने उद्योगपतियों को बख्शा नहीं। उन्होंने कहा कि उद्योगपति पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाने से कतराते हैं, किंतु वे निजी स्वार्थ के लिए अपने कारखानों को 'बीमार' बनाने में माहिर हैं। दूसरे शब्दों में उद्योगपतियों का एकमात्र उद्देश्य भारी मुनाफा कमाना है। पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाकर ऐसा करना आसान नहीं। इसलिए वे इससे कतराते हैं।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व ही सरकार ने ऐलान किया था कि पिछड़े क्षेत्रों में ५० करोड़ रुपए तक की पूंजी लगाकर कारखाना खोलने वाले को सरकार से औद्योगिक लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि ऐसे पूंजीनिवेशक को अपना *कारखाना शुरू करने के लिए कुछ भी करने की आजादी है।* उसे ऐसी अनेक *रियायतें भी मिलेंगी जो गैर* पिछड़े क्षेत्रों के पूंजीनिवेशकों को अनुपलब्ध हैं—मसलन परिवहन 'सबसिडी' (आर्थिक सहायता)। पिछड़े क्षेत्र के उत्पादक कारखाने को इसके अभाव में भारी खर्च करना पड़ता। इस सबसिडी से वस्तु को बाजार में पहुंचाने का परिवहन खर्च कम हो जाता है। इसके अलावा और फायदे भी हैं, जिनमें कर-लाभ प्रमुख है। पूंजीनिवेशक को आसान शर्तों पर कर्ज भी मिलता है। इन सबके परिणामस्वरूप कारखाने के पिछड़े क्षेत्र में होने के बावजूद उद्योगपति के लिए भारी मुनाफा सुनिश्चित होता है।

और रियायतें चाहिए: सिंघानिया का कारखाना लाइसेंसशुदा है और उसे पिछड़े क्षेत्र के वे सब लाभ प्राप्त हैं जो लाइसेंस समाप्ति की हाल की घोषणाओं के बाद खुलने वाले नये कारखानों को मिलेंगे। फिर भी सिंघानिया अपने कारखाने के कच्चे माल के लिए आसान आयात, आयात शुल्क में कटौती तथा अन्य प्रमुख रियायतें चाहते हैं। मजे की बात तो यह है कि उनके कारखाने को अनेक रियायतें पहले से ही प्राप्त हैं। किंतु सिंघानिया का कहना है कि जब तक नयी रियायतें नहीं मिलतीं, उद्योग न तो जिंदा रह सकता है, न दो-तीन वर्षों में मुनाफा कमा सकता है।

ऐसी बातों का क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि मुनाफा और अच्छा व्यवसाय तभी संभव है, जब सरकार उद्योगपतियों पर रियायतों की वर्षा करती रहे। पिछड़े क्षेत्रों में कारखाना लगाने के एवज में दी गयी रियायतें ही काफी नहीं हैं। प्रत्यक्ष करों, राजस्व व आयात शुल्कों, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर कर्ज जैसी रियायतें भी जरूरी हैं। इसके अलावा सस्ती बिजली, साज सामान, जिंसों और कारखाने के उत्पादों के परिवहन आदि पर सबसिडी अलग से मिले। संक्षेप में इसका अर्थ है कि निजी पूंजीनिवेशकों का भला करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी रियायतों के द्वारा ही सरकार पूंजीनिवेशकों के अच्छे 'लाभ' की जमीन तैयार करती है और इस तरह वह बेहतर पूंजीनिवेश का वातावरण तैयार करती है।

इसके अलावा व्यवसायियों के आम इलजाम अलग हैं। मसलन नियंत्रण बुरा है, सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नियम-कानून बनाना बुरा है। नियंत्रण और नियम निजी पहलकदमी, मुक्त प्रतिद्वंद्विता में बाधक बनकर पूंजीनिवेश के वातावरण को मंद करते हैं। ये बाधाएं क्या हैं? पहला लाइसेंसिंग है। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां कानून (एमआरटीपी) दूसरा है। इसके अलावा यह प्रावधान भी ठीक नहीं कि एकमुश्त आयात सरकारी अनुमति से ही संभव हो। व्यवसायियों को देश के बाहर किसी से कोई सामान खरीदने या बेचने की आजादी होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार के दर्शन का निचोड़ और असीम उदारीकरण की मांग का मूलाधार है। इस दर्शन का प्रचार-प्रसार करने वाले कुछ वर्षों से काफी मुखर हैं और उनकी एक प्रमुख मांग आज स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया में है। सरकार ने हाल में पिछड़े क्षेत्रों में ५० करोड़ और अन्य क्षेत्रों में १५ करोड़ पूंजीनिवेश करने वाले के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का जो फैसला लिया है, वह शायद संपूर्ण लाइसेंस प्रणाली के खातमे की दिशा में उठाया गया पहला कदम है।

यह कार्रवाई ऐसे समय की गयी है, जब प्रधानमंत्री निजी पूंजीनिवेश की कम विकास दर की समस्या के आसान हल की तलाश में थे। व्यवसायियों को पिछले तीन बजटों में नयी-नयी रियायतें प्रदान

पूर्व वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी

उद्योगपति पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाने से कतराते हैं, किंतु वे निजी स्वार्थ के लिए अपने कारखानों को 'बीमार' बनाने में माहिर हैं। दूसरे शब्दों में उद्योगपतियों का एकमात्र उद्देश्य भारी मुनाफा कमाना है। पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाकर ऐसा करना आसान नहीं। इसलिए वे इससे कतराते हैं।

की गयीं। फिर भी व्यवसायियों का दावा है कि उनके मुनाफे की दर कम होती जा रही है और सरकारी रिकार्ड भी निजी पूंजीनिवेश की विकास दर में गिरावट दर्शाता है।

इस तरह उन्हें यह नयी रिश्वत दी गयी है। यदि कंपनी एमआरटीपी कानून अथवा विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) के अंतर्गत नहीं आती, तो उसे कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं।

एमआरटीपी के अधीन आने वाली कंपनियां भीमकाय नियमित कंपनियां हैं जो किसी विशेष सामान के कुल सामान का अच्छा-खासा भाग हथियाये होती हैं। वे या तो उत्पादन करती हैं अथवा पूंजी के मामले में विशाल होती हैं। फेरा कंपनियां मुख्यत: वे हैं, जिनकी कुल पूंजी में ४० प्रतिशत से अधिक विदेशी निजी पूंजी लगी होती है। उन्हें भी नयी रियायतें हासिल नहीं हैं। शेष के लिए पूरी आजादी है। वे जो चाहें और जितनी मात्रा में चाहें, उत्पादन करें। आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं।

पिछड़े क्षेत्र का विकास?: कोई व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि ५० करोड़ की सीमा तक लाइसेंस खतम करना पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छा है। इस दिशा में अब तक उठाये गये अधिकांश कदम पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में नाकाम साबित हुए हैं। इन तमाम रियायतों के बावजूद बड़े पूंजीनिवेशकों ने अपने कारखाना-स्थल के लिए पिछड़े क्षेत्र का चुनाव नहीं किया है। यदि किसी ने ऐसा किया भी है, तो उसने इस बात को ध्यान में रखा कि उसका प्लांट जिला नगर अथवा राज्य की राजधानी के बहुत करीब हो।

इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से जो क्षेत्र १९४७ में पिछड़े थे, वे आज भी लगभग पिछड़े बने हैं। यह स्थिति भारत के ३८० में से २०२ जिलों की है। इन क्षेत्रों में पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने का एक तरीका बड़े पूंजीनिवेशकों को इन क्षेत्रों को चुनने की इजाजत देना है। इस प्रकार ५० करोड़ की हदबंदी बड़ी मात्रा में पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करेगी और इससे स्थिति सुधारने में भारी मदद मिलेगी।

यहां तक तो ठीक है। किंतु लाइसेंस खतम करना जरूरी था? क्या अधिक पूंजी निवेश पिछड़े क्षेत्रों में इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि पूंजीनिवेशकों ने इसके लिए जो लाइसेंस मांगा था, वह दिया नहीं गया? औद्योगिक लाइसेंस के कितने आवेदन पत्रों को नामंजूर किया गया था? नामंजूर आवेदनों में कितने पिछड़े क्षेत्रों में कारखाना लगाने से संबंधित थे?

इन सवालों के जवाब से ऐसी दलीलों का समर्थन नहीं होता कि लाइसेंस खतम करने से विकास को बड़ा बल मिलेगा। दूसरी ओर यह बड़ी पूंजी से सस्ते श्रम का शोषण करने, तमाम रियायतों से भारी मुनाफा कमाने और साथ-ही-साथ मध्यम प्रकार की तमाम पूंजी निवेश की संभावना को समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

लाइसेंस प्रणाली समाप्त होने पर यह सब एक व्यक्ति के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि उसकी व्यापार बुद्धि तेज है, तो वह सफल हो सकता है और वह तभी शक्तिशाली बन सकता है, जब उच्च क्षमता वाला काफी बड़ा प्लांट लगाये, जिससे उसकी लागत उसके प्रतिद्वंद्वियों से नीची रहे।

कुछ भी हो, ५० करोड़ रुपए एक बड़ी पूंजी है। उससे भारी यंत्रों वाले विशाल कारखाने लगाये जा सकते हैं। मसलन चार पहिया वाहन डीसीएम-टोयटा प्लांट १३ करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से लगाया गया था। ५० करोड़ रुपए की लागत से कोई भी मध्यमश्रेणी का सीमेंट कारखाना, चंद सूती मिलें अथवा महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन उत्पन्न करने वाला कारखाना लग सकता है।

असली मकसद: दरअसल यह नया फैसला औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को ही खतम करने की ललक से प्रभावित प्रतीत होता है। यह आम उदारीकरण की नीति और शासक दल के महारथियों द्वारा चुनावी और अन्य लाभ प्राप्त करने का भी एक हिस्सा है। पहले राजनीतिक फायदों को लें। यदि आप किसी उद्योगपति को अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्री लगाने को प्रेरित कर लें, तो आपका राजनीतिक कद बढ़ जायेगा। आपको महज उद्योगपति से अनौपचारिक तालमेल बिठाना पड़ेगा, जिससे उसे अहसास हो कि उनका व्यावसायिक हित पूरी तरह सुरक्षित है। यदि राज्य का मुख्यमंत्री आपका मित्र है, तो आप बेहतर सड़कों, बिजली तथा ऐसी अन्य जरूरी जिंसों की फौरी और गारंटीशुदा सप्लाई का वायदा कर सकते हैं।

यदि यह सही नहीं, तो किस प्रकार शासक पार्टी के उच्च पदस्थ लोगों के निर्वाचन क्षेत्र औद्योगिक रूप से बेहतर हैं? वहां बड़ा पूंजीनिवेश किस प्रकार संभव हुआ? निस्संदेह आला राजनीतिक हस्तियों ने व्यावसायिक क्षेत्र के अपने मित्रों की आर्थिक संभावनाओं का विस्तार किया होगा। लाइसेंस उन्मूलन से रास्ता और आसान हो जायेगा। नौकरशाहों की दखलंदाजी खतम हो जायेगी, परियोजना की संभावनाओं के विषय में विशेषज्ञों के मूल्यांकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार कैबिनट उपसमिति का भी कोई दखल इस मामले में नहीं रह जायेगा। जरूरत होगी, तो मात्र राजनीतिक हस्ती की अनुकंपा की। उसी के सहारे उद्योगपति फले फूलेगा। वह उतना अधिक पान-फूल चढ़ाने को उद्यत होगा, जितना अधिक उसका व्यावसायिक हित सधता नजर आयेगा।

गैर पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंस के खातमे की सीमा को भी लें। १५ करोड़ रुपए तक के पूंजीनिवेश को किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी (पहले सीमा ५ करोड़ की थी)। इस छूट का बहरहाल पिछड़े क्षेत्रों के विकास से कुछ लेना-देना नहीं। फिर इसकी सीमा इतनी अधिक क्यों बढ़ायी गयी? क्या इसकी वजह यह है कि गत कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण रुपए का वास्तविक मूल्य बहुत घट गया है और परियोजना लागत बहुत बढ़ गयी है? यह कुछ अर्थों में सही है।

किंतु क्या परियोजना लागत गत १०-१२ वर्षों में तीन गुना बढ़ गयी है? यदि ऐसा नहीं है, तो ५ करोड़ से बढ़ाकर १५ करोड़ रुपए क्यों किया गया? यह सब सरकार की नीति में परिवर्तन का नतीजा है। यह राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद आरंभ हुई उदारीकरण की स्थायी नीति का एक और अगला चरण है। इसकी मंजिल है मुक्त बाजार का अर्थतंत्र।

योजना को अलविदा: यह समझना मुश्किल नहीं कि लाइसेंस खतम करने का सीधा अर्थ होगा कि उत्पादन या पूंजीनिवेश के लिए न तो किसी केन्द्रीकृत योजना की दरकार रह जायेगी, न सरकारी नियमों की। व्यवसायी अपने लाभ की संभावनाओं का स्वयं मूल्यांकन करके तब तक अपने फैसले पर अमल करते हैं, जब तक वे पूंजी एकत्र कर सकते हैं। मसलन यात्री कार का आज निर्माण तभी किया जा सकता है, जब पूंजी निवेशक के पास लाइसेंस हो। उसे अनुमति अनेक मामलों में संतुष्ट होने के बाद ही दी जाती है: जैसे भावी मांग, संसाधनों की स्थिति, कार की किस्म, ईंधन खपत, अनुमानित मूल्य, आयात जरूरतें आदि।

लाइसेंस प्रणाली समाप्त होने पर यह सब एक व्यक्ति के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि उसकी व्यापार बुद्धि तेज है, तो वह सफल हो सकता है और वह तभी शक्तिशाली बन सकता है, जब उच्च क्षमता वाला काफी बड़ा प्लांट लगाये, जिससे उसकी लागत उसके प्रतिद्वंद्वियों से नीची रहे।

ऐसी स्थिति में पूंजी का प्रवाह

मूल्य रु० ५/-

पावस-विशेषांक

कुछ प्रमुख आकर्षण

पाप और प्रायश्चित

शराब और शराब

हनीमून

महबूबा की बारात

रेगिस्तान के उस पार

संघर्ष और सफलता

मनोहर कहानियाँ
अतिरिक्तांक
हनीमून
(रहस्य-रोमांच कथा)
बंगाल का फकीर विद्रोह
राजमाता का प्रतिशोध
(इतिहास कथा)
मूल्य ५-००

साथ ही अन्य अनेक दिलचस्प सत्यकथायें

मनोहर कहानियाँ अतिरिक्तांक

जून के अन्तिम सप्ताह तक प्रकाश्य

अधिक मुनाफा वाले क्षेत्रों में होगा। इसमें कुछ नाकाम रहेंगे और कुछ कामयाब। जो नाकाम रहेंगे, वे क्षमता से कहीं कम उत्पादन करेंगे। इसका अर्थ होगा पूंजी व्यर्थ जायेगी। हर कोई धनी उपभोक्ता के लिए सामान बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो जायेगा। क्योंकि यही वर्ग ऊंची कीमत अदा करने की स्थिति में है। तब ऐसे सामान जिन्हें आम आदमी फैक्ट्री मजदूर, किसान आदि इस्तेमाल करते हैं, पर आज के बराबर भी पूंजीनिवेश नहीं हो पायेगा।

ऐसा ही अहम मुद्दा बेरोजगारी का है जो तेज रफ्तार से बढ़ेगी। निर्माण उद्योग तकनीक और विदेशी सहयोग को पसंद करेगा। मसलन सिंघानिया का खटीमा प्लांट पश्चिम जर्मनी के सहयोग से खुला है। वह उच्च तकनीक वाली परियोजना है। किंतु १०० करोड़ रुपए के सिंघानिया के प्लांट में महज ४०० कर्मचारी हैं। इसका मतलब हुआ कि एक आदमी को रोजगार देने के लिए प्लांट को २५ लाख रुपए की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में एक पूर्णकालिक रोजगार का अवसर जुटाने के लिए इतनी अधिक पूंजी लाजिमी है।

व्यवसायी का रोजगार मुहैया करने से कोई वास्ता नहीं होता। उसकी दिलचस्पी तो कम लागत के उत्पादन की व्यवस्था में होती है। वह घटी दर पर उत्पादन के लिए अधिक पूंजी लगाना चाहेगा। इसका मतलब होगा कम-से-कम वेतन लागत। यदि अच्छे मुनाफे के लिए यह जरूरी हो गया और सब इसी ढर्रे पर चलने लगे, तो रोजगार में बढ़ोतरी की संभावना धूमिल हो जायेगी। इस मार्ग से उत्पादन वृद्धि से आर्थिक विकास तो होगा, किंतु रोजगार में या तो नाम मात्र की या कतई वृद्धि नहीं होगी। यह भारत जैसे अविकसित अर्थतंत्र के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। गरीब और गरीब होता जायेगा और धनी विकास ढांचे का और मजबूत पाया बनता जायेगा।

उद्योगीकरण की लाइसेंस विहीन प्रणाली में ऐसा होना लाजिमी है। यूरोप, अमरीका व जापान में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि वहां जरूरी जिंसों की ऐसी किल्लत नहीं जो भुखमरी की नौबत पैदा करे। किंतु राजीव गांधी, राष्ट्रपति रीगन, मार्गरेट थैचर और विश्व बैंक का आर्थिक विकास का दृष्टिकोण समान है। हां, एक फर्क जरूर है। राजीव गांधी और उनकी सरकार व्यवसायियों से परोसी थाली से भूख मिटाने और भोजन बचाने दोनों की उम्मीद करते हैं।

नियंत्रण, लाइसेंस, नियम और व्यवसायियों को नापसंद अन्य प्रावधानों को एक-एक करके खतम किया जाये, किंतु इसके साथ ही रियायतें जारी रहनी चाहिए। व्यवसायी बेरोकटोक आयात, सामान की ढुलाई में सबसिडी, सस्ती बिजली, अच्छी सड़क व रेल यातायात, आधुनिक दूर संचार, कम ब्याज पर कर्ज और कर रियायतें चाहते हैं। वे सरकारी दखलंदाजी से आजादी के साथ-साथ राज्य से हर प्रकार की रियायतें हासिल करने की भी आजादी चाहते हैं। ये तमाम रियायतें आम करदाताओं को अदा करनी पड़ती हैं। यह ऐसा बहुसंख्यक वर्ग है जो बेहद गरीब है और कभी-कभार सामुदायिक केन्द्र के टीवी सेट की झलक के अलावा उच्च तकनीक के फलों से कोरा है। इस प्रकार लाइसेंस खतम करना और रियायतों की टोकरी भरते जाने का अर्थ व्यवसायियों के लिए क्या होगा, इसको समझना मुश्किल नहीं। इसका मतलब है कि व्यवसायी ऐसे मुक्त बाजार के अर्थतंत्र में स्वास्थ्य लाभ करना चाहता है जो राज्य के दायरे से इन दो मायनों में मुक्त हो: राज्य की पूंजीनिवेश के मामले में कोई दखलंदाजी न हो और उसके प्रति राज्य की पूरी वफादारी, जिससे उसके (व्यवसायी के) मुनाफे की अंततः उस गरीब आदमी से गारंटी हो जो सरकारी धन के अधिकांश भाग की अदायगी करता है। सीताराम सिंघानिया ने यही मांग खटीमा के समारोह में की थी। उन्होंने सम्मानजनक ढंग से यह बात कही थी, किंतु वित्त मंत्री तिवारी नाराज हो गये और उनका (सिंघानिया का) कच्चा-चिट्ठा पेश कर दिया। किंतु दोनों को ही असलियत का पता है। कम-से-कम हाल के लाइसेंस में छूट के अर्थ से वे बखूबी परिचित हैं।

—अर्थ विज्ञानी

TRANSWORLD TRADEFARE
— GOLD MEDAL —
SELECTION AWARD

1987

लोकप्रिय
खेतान वॉशिंग पाव्डर व नहाने का साबुन
अब, स्वर्ण-पदक से भी अलंकृत!

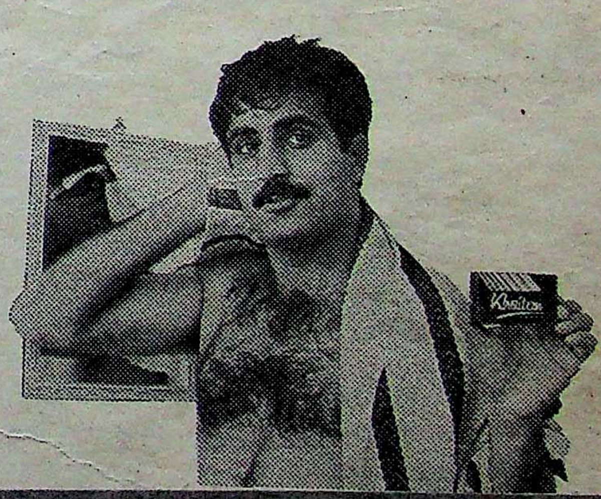

- उजलापन और सफेदी का किफ़ायती राज़।
- खेतान वॉशिंग पाव्डर ... कपड़ो में छुपे मैल पर जल्द असर करे।

सारे परिवार के लिये एक सम्पूर्ण साबुन।
खेतान लाल टिकिया ... तन्दुरुस्ती के संग-संग अब, ताज़गी भी।

खेतान केमिकल्स लि.
ए-94/1, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020.

naa/D/KCL-88

साक्षात्कार/**श्रीदेवी**

मैं 'हीरो-वर्शिप' में विश्वास नहीं करती

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्व० नर्गिस के लगभग तीन दशक बाद, पहली बार एक ऐसी अभिनेत्री का उदय हुआ, जिसने पुरुष नियंत्रित फिल्म उद्योग में सिर्फ अपने बलबूते अपना वर्चस्व कायम किया। नर्गिस की तरह न केवल उसने अपनी 'डिमांड प्राइस' पैदा की, बल्कि सुपर स्टारों के वर्चस्व को यह कह कर तोड़ने का दुस्साहस भी किया कि 'मुझे पहले स्क्रिप्ट चाहिए। हीरो कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके मुकाबले अगर मेरी भूमिका मामूली है, तो मैं वह फिल्म नहीं करूंगी अथवा स्क्रिप्ट को बदलना पड़ेगा।'

जिस तरह सिर्फ नर्गिस के नाम पर फिल्में फिल्म मार्केट में मुंहमांगी कीमत पर बिक जाया करती थीं, उसी तरह वितरक इस अभिनेत्री के नाम की घोषणा होते ही फिल्म निर्माता को मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं अथवा फायनेंसर कम ब्याज पर भी फिल्म को फायनेंस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इस अभिनेत्री का नाम फिल्म मार्केट में 'गारंटी' माना जाता है और हर कोई अपने लगाये धन को महफूज समझता है कि अगर फिल्म बाक्स आफिस पर हिट नहीं भी हुई, तो लाभ के साथ 'रिटर्न' दे ही जायेगी। इस गारंटी का नाम है—श्रीदेवी।

श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री की न तो लीजेंड है, न वीनस—और न ही श्रीदेवी शबाना, स्मिता या अपर्णा सेन जैसी इंटेलेक्चुअल जमात की अभिनेत्री है और न ही होने का दावा करती है। 'स्टारडम' की परिभाषा पूछिए, तो कह देगी—'सुबह उठने से लेकर गयी रात तक सोने के पहले फिल्म की शूटिंग में अति व्यस्त रहना।' और इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट की परिभाषा यों देगी—'जो पढ़ते तो बहुत हैं, बातें भी बहुत कर लेते हैं, तर्क-वितर्क भी कम नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पाते।' किशोरियां श्रीदेवी की इसलिए दीवानी हैं कि श्रीदेवी उनकी जैसी लगती है, परदे पर बातचीत भी उनके ही अंदाज में करती है। युवतियों-अधेड़ महिलाओं को श्रीदेवी इसलिए पसंद है कि उसके चेहरे-हावभाव में नैसर्गिक भोलापन है, दूसरी अभिनेत्रियों जैसी नारी-सुलभ कुटिलता और चालाकी-भरा अंदाज नहीं। हर उम्र के पुरुष उसे इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें (श्रीदेवी) रति जैसा आकर्षण है, तो अप्सराओं जैसी खूबसूरती और किन्नरियों जैसी सम्मोहन-शक्ति। इसीलिए श्रीदेवी, अपने से अधिक खूबसरत लावण्यमयी जयाप्रदा तथा अत्यधिक ग्लैमरस-सेक्स प्रतीक रेखा पर भारी पड़ती है।

४ वर्ष की उम्र में अभिनय के जादुई-भरे संसार में उत्तर आनेवाली श्रीदेवी 'जूली' के तल्ख अनुभव को आज भी नहीं भूल पाती। 'जूली' में उसने लक्ष्मी की छोटी बहन की भूमिका निभायी थी और सेट पर 'कुछ' कलाकार जब उससे जूनियर आर्टिस्ट जैसा व्यवहार करते थे, तो वह स्टूडियो के एक कोने में जाकर आंसू बहा लेती थी फिर इस दृढ़ निश्चय के साथ सेट पर, आंखें पोंछते हुए आ खड़ी होती थी—'मैं तुम सबको एक दिन 'बीट' कर दूंगी।' वह तब उस मेकअप मैन की घुड़की भी बरदाश्त कर लेती थी, जब रोने के कारण खराब हो गये मेकअप को ठीक करते हुए कई बार बुरी तरह से डांटा जाता था। लक्ष्मी की तरह श्रीदेवी ने भी तब 'जूली' को 'हिंदी फिल्मों में प्रवेश का द्वार' माना था। जूली बाक्स आफिस पर सुपर हिट हुई थी, लेकिन किसी भी कलाकार के लिए 'गेटवे आफ फिलमडम' नहीं बन सकी थी।

छाया : तैयब बादशाह

श्रीदेवी को उसके पिता एडवोकेट बनाना चाहते थे, मां अभिनेत्री। अंततः मां की जीत हुई—श्रीदेवी कक्षा ७ की पढ़ाई अधूरी छोड़ कर पूरी तरह फिल्मों के प्रति समर्पित हो गयी। "जब मैं सेट पर आती हूं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ फिल्म का कैरेक्टर रहता है, जिसे मैं कैमरे के सामने ऐक्ट करनेवाली होती हूं। सेट पर आने के पहले मैं उस किरदार का पूरी तरह से अध्ययन कर लेती हूं, इसलिए किरदार कैसा भी हो उसे 'ऐक्ट' करते समय मुझे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। सब कुछ स्वतः हो जाता है।"

श्रीदेवी को संगीत पसंद है, विशेषकर पश्चिमी संगीत—डिस्को, पॉप, जाज। और इनके ढेर सारे एलबम उसके पास हैं। वह मानती है कि 'इस संगीत में शोर-शराबा तथा 'फास्टनेस' बहुत है, लेकिन काम से थके हुए मन को यह राहत भी प्रदान करता है, क्योंकि इसे समझने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता—शरीर में अपने आप थिरकन आने लगती है।' उसे मिठाई और आइसक्रीम बहुत पसंद है। भोजन में चावल व दही तो होना ही चाहिए। विदेशी व्यंजनों में चाइनीज डिशेज ज्यादा भाती हैं। समचे विश्व में वह सिर्फ दो व्यक्तियों की प्रशंसक/भक्त है—मां और महात्मा गांधी की। भगवान में पूरी आस्था है। चार्ली चैपलिन को बतौर अभिनेता वह काफी पसंद करती है। पिछले एक दशक में वह अकेली अभिनेत्री रही है, जिसकी दो फिल्मों ने ('नगीना' एवं 'मि० इंडिया') एक साथ बाक्स आफिस पर नये कीर्तिमान कायम किये, जिसकी कई फिल्में लगातार फ्लाप हुईं, लेकिन उसके मार्केट या कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्रीदेवी की सफलता और लोकप्रियता का राज भले ही कुछ हो, लेकिन फिल्मवाले उसे कतई नापसंद नहीं करते, क्योंकि वह न तो फिल्मी राजनीति में पड़ती है और न ही कभी किसी के फटे में पांव उलझाती है। किस अभिनेत्री को कौन निर्माता साइन कर रहा है या निकाल रहा है, इस बारे में न तो वह बात करना पसंद करती है, न ही इस पचड़े में पड़ना। प्रस्तुत हैं, श्रीदेवी से 'माया' की बातचीत के मुख्य अंश :

माया : ***क्या यह फिल्म इंडस्ट्री का दुर्भाग्य नहीं कि जो कलाकार कभी प्रेस और पत्रकार के आगे-पीछे चक्कर लगाते नहीं थकते थे, वही सुपर स्टार बनते ही उन्हें घटिया दर्जे का इंसान मान लेते हैं और अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर देते हैं।***

श्रीदेवी : *(बच्चों जैसे भोलेपन के साथ) मैं आपका मतलब नहीं समझी। क्या वाकई ऐसा होता है, मसलन जैसे ?*

माया : ***अमिताभ बच्चन तथा रेखा। क्या आप भी इन दोनों सितारों की राह पर चल निकली हैं ?***

श्रीदेवी : *यह किसने कह दिया आपसे ? उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। हां, सफलता के साथ व्यस्तता बढ़ती जाती है कि अपनों के लिए भी समय निकाल पाना बहुत कठिन होता है। कभी-कभी तो बहुत कोफ्त होती है कि ऐसी भी क्या जिंदगी, ऐसी भी क्या व्यस्तता कि आदमी अपनों से ही कट जाये।*

माया : ***लेकिन मेरे सवाल का यह जवाब तो नहीं।***

श्रीदेवी : *है। जब आदमी अपनों से कट जाता है, तो दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका सारा दूसरों (फिल्म निर्माताओं) के पास गिरवी जैसा रख दिया गया होता है जो है तो उसका, लेकिन उस पर उसका खुद का कोई अधिकार नहीं है। अब आपका सवाल। मेरी सफलता में प्रेस का उतना ही बड़ा हाथ है, जितना मेरी तकदीर का। मेरी दिली इच्छा रहती है कि रोजाना एक पत्रकार से बात करूं—लेकिन कब किस समय ? १० से [illegible] घंटे तक लगातार काम करती हूं। काम के दौरान बात करूं, तो फिल्म निर्माता का नुकसान होता है, क्योंकि सेट पर अथवा डबिंग के समय उसका एक-एक सेकंड कीमती होता है। मैंने अगर किसी से*

१५

मिनट बात की, तो उसका एक घंटा जाया होता है। फिर भी मैंने आज तक किसी पत्रकार को वापस नहीं किया।

माया : व्यस्तता की इस रफ्तार में क्या आपको नहीं लगता कि आप भी (स्व०) मीना कुमारी या रेखा जैसी ग्लैमरस, लेकिन कुंठाग्रस्त अकेलेपन की जिंदगी जीने का खतरा मोल ले बैठी हैं?

श्रीदेवी : आप ठीक कहते हैं, इस बात को मैंने शुरू में भांप लिया था, इसलिए मैंने अपने को परिवार से कटने नहीं दिया। दूसरे सितारों की तरह मैं नींद की गोलियां नहीं लेती। अपने काम को पूरी मेहनत से निबटाती हूं, लेकिन बेकार के तनाव में नहीं जीती। इसलिए उस खतरे की संभावना फिलहाल तो नहीं है।

माया : मतलब हो सकता है?

श्रीदेवी : (तमक कर) नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैं सिंह राशि की हूं। अगर एक बार निर्णय कर लिया, तो निर्णय कर लिया। लेकिन निर्णय मैं जल्दबाजी में नहीं, पूरे विवेक में सोच-समझ कर करती हूं।

माया : क्या यह आत्मविश्वास का अतिरेक नहीं है कि आप उस अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना करती हैं, जिनके साथ काम करने के लिए आप कभी लालायित थीं?

श्रीदेवी और जीतेंद्र 'घर संसार' में

छाया : प्रदीप एन राम

राकेश रौशन और श्रीदेवी 'जाग उठा इंसान में'

छाया : प्रदीप एन राम

श्रीदेवी : लालायित? (हंसकर) आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है। मैं हीरो-वर्शिप (नायक-पूजा) में विश्वास नहीं करती, न ही कभी मेरी इच्छा किसी विशेष कलाकार के साथ काम करने या उस जैसा काम करने की रही है। और न ही कभी किसी फिल्म निर्माता से पूछती हूं कि मेरा अपोजिट स्टार कौन है या उस पर दबाव डालती हूं कि वह 'फलां' कलाकार को ही मेरे साथ साइन करे। (कुछ सोचकर) कुछ वर्ष पहले एक पत्रकार ने पूछा, "आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम नहीं कर रहीं?", तो मैंने उनसे कहा, "वह बढ़िया अभिनेता हैं, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया, तो जरूर काम करूंगी।" और किया भी।

माया : तो ऐसी क्या बात हो गयी कि आपने...

श्रीदेवी : (बात काट कर) नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया। हां, उनके साथ काम करने का आफर लानेवाले निर्माताओं से जरूर मैंने पूरी स्क्रिप्ट मांगी थी।

माया : क्यों?

श्रीदेवी : इसलिए कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों की स्क्रिप्ट सिर्फ उन्हें ही ध्यान में रखकर लिखी जाती है, उसमें हीरोइन की कोई भूमिका ही नहीं होती। जैसी भूमिका होती है, मैं वैसी करना नहीं चाहती।

माया : आपने ऐसी गैरमहत्वपूर्ण भूमिकाएं की हैं।

श्रीदेवी : कभी-कभी कोई भूमिका अनिच्छावश स्वीकार करनी पड़ती है—कुछ दबाव होते हैं, कुछ दोस्ती या ऐसे रिश्तों के कारण मना नहीं करते बनती।

माया : शशि कपूर का कहना है कि 'अजूबा' के लिए आपने उन्हें मद्रास के अनेक चक्कर लगवाये और अंत में काम करने से मना कर दिया।

श्रीदेवी : ऐसा कहा उन्होंने? मुझे विश्वास नहीं होता। खैर, मैं असली बात बतला रही हूं। मैं बचपन से शशिजी की 'फैन' रही। मैं उनकी फिल्म 'अजूबा' जरूर करना चाहती थी, लेकिन १९८८ में जो-जो शिड्यूल डेटें वह चाहते थे, मैं १९८७ में दूसरे निर्माताओं को दे चुकी थी। मेरी डेट्स के आधार पर इन निर्माताओं ने दूसरे कलाकारों की डेट्स लेकर शूटिंग शिड्यूल बना लिया था। शशिजी को डेट्स देने पर उन निर्माताओं को लाखों रुपए की हानि होती। दूसरों की कब्र पर मैं अपना महल नहीं बना सकती। शशिजी एक जमाने के सबसे व्यस्त कलाकार रहे हैं। वह मेरी परेशानी समझ सकते हैं और उन्होंने समझा भी। रही मद्रास दौड़ने की बात, तो वह खुद आये थे। मैंने उनसे कहा भी कि आप १९९० में कोई फिल्म प्लान कीजिए—स्टार्ट टु फिनिश। मैं सारी डेटें अभी आपको दिये देती हूं।

माया : क्या आपने देवआनंद की फिल्म इसलिए मना कर दी कि उसमें कई हीरोइनें थीं या वह पैसा कम दे रहे थे?

श्रीदेवी : नहीं, वह बढ़िया पे-मास्टर और ईमानदार फिल्म मेकर हैं। उनके साथ भी सिर्फ 'डेट्स' की समस्या थी।

माया : रेखा और जयाप्रदा भी आपकी तीखी आलोचना करती हैं। रेखा का कहना है कि उन्होंने मेकअप, खूबसूरत दीखने तथा बंबइया फिल्म इंडस्ट्री को काबू में रखने के गुर आपको सिखलाये। आपको नंबर वन का दर्जा देने के लिए खुद आपके रास्ते से

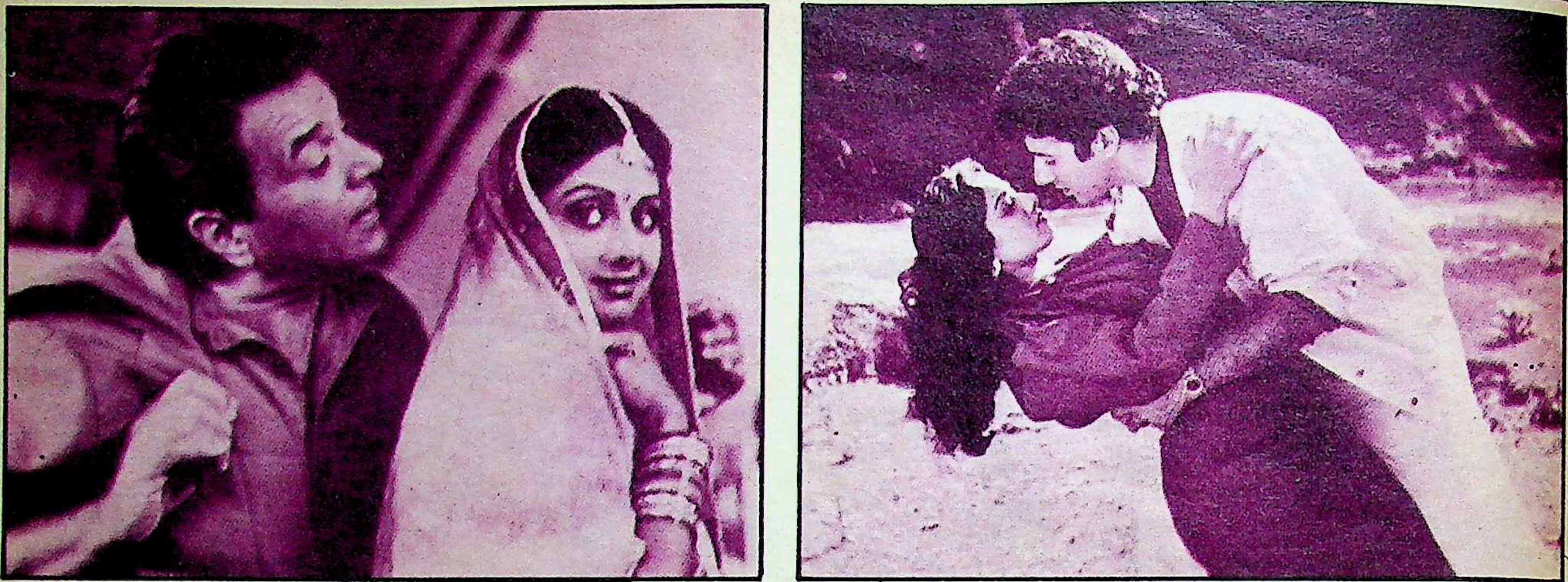

बाप-बेटे दोनों की हीरोइन: श्रीदेवी 'नाकाबंदी' में धर्मेंद्र के साथ (बायें), सनी देवल के साथ (दायें)

हट गयीं। जयाप्रदा आपको अतिआत्मविश्वासी, बेहद गुरूरी तथा 'जीरो एस्थेटिक सेंस' वाली अभिनेत्री मानती हैं।

श्रीदेवी: *(तमक कर) जीरो एस्थेटिक सेंस, ऐसा कहा उन्होंने? (संभलकर) मैं आपको दोनों आरोपों का जवाब दूंगी। रेखा मुझसे सीनियर जरूर हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम दोनों एक साथ फिल्मों में आयीं—वह बतौर हीरोइन और मैं दक्षिण की फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में। मेरी उनसे दोस्ती बंबई में इसलिए हुई, क्योंकि मैं और वह तेलुगू जानती थीं, तब मुझे हिंदी बिलकुल नहीं आती थी। आप किसी भी अनजान जगह पर जायें, तो आपकी दोस्ती अपनी भाषा, अपने प्रदेश वाले से पहले होगी, क्योंकि वहीं पर आप अपने को 'कम्यूनिकेट' कर सकते हैं। मेरी जैसी समस्या दक्षिण से आयी दूसरी अभिनेत्रियों की नहीं थी। रही मेकअप या खूबसूरती की बात, तो मैं बंबई आने के पहले दक्षिण की फिल्मों में नंबर वन सुपर स्टार थी। मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी। हां, बंबइया फिल्मवालों के बारे में वह जरूर तीखी-मीठी बातें तथा अपना अनुभव सुनाती थीं। लेकिन 'दूसरों' की बातों या अनुभव के आधार पर आप किसी के बारे में निर्णय नहीं बना सकते।*

माया: ***इस 'दूसरों' में आप जयाप्रदा को भी शामिल करती हैं, वह आपकी इतनी बुराई क्यों करती हैं?***

श्रीदेवी: *नहीं, मैं किसी-में-किसी को शामिल नहीं करती। वह मुझसे खफा क्यों हैं, मुझे पता नहीं। आप उनसे पूछ कर बतला दीजिए। (कुछ सोचकर) यह उनका अपना 'ईगो प्राब्लम' हो सकता है।*

माया: ***आपको 'मामा' ज मैन' कहा जाता है यानी आप खड़ी होती हैं या बैठती हैं, तो वह भी अपनी मां के इशारे पर।***

श्रीदेवी: *'मामा' ज मैन' मुहावरे को बदलकर 'मम्मी' ज डाटर' कहिए। मैं मम्मी के बिना अपने को हंड्रेड परसेंट माइनस महसूस करती हूं। यों भी मां से बड़ी कोई दूसरी शख्सीयत इस पृथ्वी पर नहीं है। आप सोचिए भला, मम्मी ने आम मांओं की*

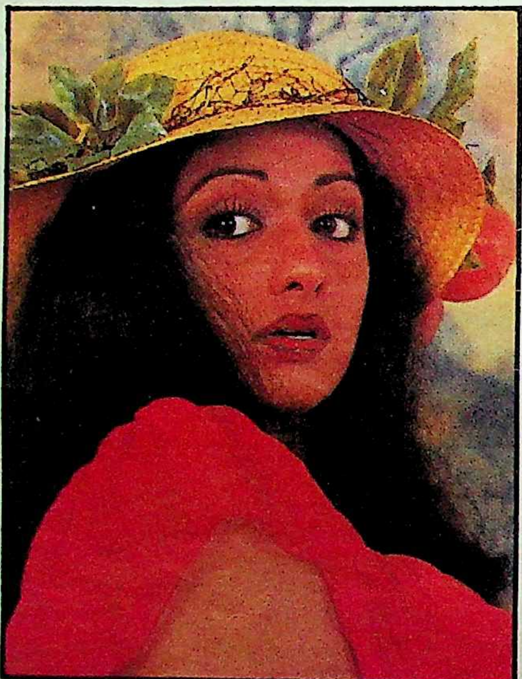

छाया: तैयब बादशाह

तरह सिर्फ मुझे जन्म भर नहीं दिया या पाल-पोस कर बड़ा भर नहीं कर दिया, बल्कि मेरी पथ-प्रदर्शक रहीं, कठिन-से-कठिन क्षणों का कैसे सामना करना चाहिए, इसका आत्मविश्वास मेरे भीतर पैदा किया, असंभव को संभव करना तथा बड़ी-से-बड़ी समस्याओं को निपटना सिखलाया। ऐसे में जब कोई 'मामा' ज डाटर' कहता है, तो मुझे फख्र होता है।

माया: ***आप धर्मेंद्र के साथ भी काम कर रही हैं और उनके बेटे के साथ भी। बाप-बेटे दोनों की हीरोइन बनने में क्या कुछ अटपटा नहीं लगता?***

श्रीदेवी: *अटपटा क्यों लगेगा? हेमामालिनी राजकपूर की भी हीरोइन थीं, उनके दोनों भाइयों (शम्मी कपूर व शशि कपूर) तथा बेटों (रणधीर कपूर व ऋषि कपूर) की भी हीरोइन बन चुकी थीं। फिल्म में हम स्टार के साथ नहीं, कहानी के किरदार के साथ काम करते हैं—वह किरदार कोई भी कलाकार हो सकता है। अगर कोई फिल्म निर्माता एक ही फिल्म में उन्हें (धर्मेंद्र व सनी देवल) ले और उनके 'पेयर' के रूप में मुझे, तो मैं वह रोल भी करूंगी।*

माया: ***पिछले पांच वर्षों में आपकी 'प्राइस' में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह 'प्राइस' बढ़ाता कौन है? आप, आपकी मम्मी या कोई और?***

श्रीदेवी: *आप तो इनकम टैक्स अधिकारियें की तरह बात करने लगे। (कुछ देर तक आंख मूंदकर सोचती है, जैसे क्या कहे क्या नहीं कहे) दरअसल 'प्राइस' का उतार-चढ़ाव फिल्म की सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। फिल्म निर्माता तथा वितरक फिल्म की सफलता के आधार पर बढ़ाते हैं। लेकिन बढ़ाने या घटानेवाला असली व्यक्ति होता है—दर्शक।*

माया: ***आपने 'सदमा' जैसी बेहतरीन फिल्में कम की हैं और 'हिम्मतवाला' जैसी फिल्में सर्वाधिक। कभी सोचा है आपने इसके बारे में?***

श्रीदेवी: *हां, हमेशा। जब कोई 'सदमा' में मेरे अभिनय की तारीफ करता है, तो मुझे लगता है कि वह मुझे पुरस्कार दे रहा है। मुझे आज भी खलता है कि लोग मुझे 'सदमा' जैसी फिल्मों में काम करने के लिए क्यों नहीं कहते?*

माया: ***क्या आपको पता था कि 'नगीना' और 'मि॰ इंडिया' बाक्स आफिस पर इस कदर सुपर हिट होगी?***

श्रीदेवी: *जब मुझे 'नगीना' की कहानी सुनायी गयी, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इस रोल को ठीक से निभा पाऊंगी। फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी; तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार करना तय किया। 'मि॰ इंडिया' में भी मेरा रोल 'फैंटास्टिक' था। कामेडी भूमिकाएं मुझे पसंद रहीं। इन दोनों फिल्मों की सफलता के बारे में मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन ये इस कदर हिट होंगी तब सोचा नहीं था।*

माया: ***अब किस तरह का रोल करना चाहती हैं?***

श्रीदेवी: *कोई जोरदार चरित्र भूमिका तथा एक डांसर की भूमिका।*

—रवींद्र श्रीवास्तव

देश

१६ जून : देश के सबसे महत्वपूर्ण इलाहाबाद संसदीय उपचुनाव में ४७ प्रतिशत मतदान। पंजाब में कांग्रेसी नेता बख्शीस राम की हत्या। गिरीश कर्नाड संगीत नाटक अकादमी के नये निर्देशक नियुक्त।

१७ जून : पाली संसदीय सीट पर कांग्रेस के शंकरलाल तथा सिरसा संसदीय सीट पर लोकदल (ब) के हेतराम विजयी। विधानसभा की ६ घोषित सीटों में चार पर विपक्ष विजयी।

१८ जून : इलाहाबाद उपचुनाव में जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह १ लाख १० हजार ९४६ मतों से विजयी।

१९ जून : ऊधमपुर संसदीय उपचुनाव क्षेत्र की मतगणना स्थगित। पालम हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त।

२० जून : पंजाब सरकार द्वारा पूरा प्रदेश अशांत घोषित। सरकार द्वारा एयर मार्शल सुरेंद्र मेहरा को नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष एम नरसिम्हन का त्यागपत्र। कर्नाटक विधान परिषद के लिए स्नातक एवं शिक्षक वर्गों से चुनी जाने वाली सभी छह सीटों पर जनता पार्टी पराजित। नवगठित इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एन कल्याण सुंदरम का देहांत।

२१ जून : चुनाव आयोग की तीन सदस्यीय टीम का फरीदाबाद में हुए उपचुनाव में गड़बड़ी की जांच के लिए दौरा।

२२ जून : ऊधमपुर संसदीय चुनाव का परिणाम चुनाव आयुक्त के निर्देश पर घोषित होने से रुका। 'द हिन्दू' में बोफोर्स तोप सौदे में दलाली विन चड्ढा की कंपनी स्वेंस्का को दिये जाने से संबंधित दस्तावेज प्रकाशित।

२३ जून : बोफोर्स कंपनी के पूर्व एजेंट विन चड्ढा और उनके पुत्र हर्ष चड्ढा द्वारा ८ जुलाई से पूर्व विदेश न जाने का लिखित वचन। कुख्यात आतंकवादी मिल्कियत सिंह द्वारा जहर खाकर आत्महत्या।

गिरीश कर्नाड

सुभाष घीसिंग

२४ जून : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चह्वाण एवं उ०प्र० के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह द्वारा इस्तीफा।

२५ जून : केंद्रीय मंत्रिमंडल में ६ नये सदस्य शामिल। उप्र में नारायण दत्त तिवारी तथा महाराष्ट्र में शरद पवार मुख्यमंत्री बने।

२६ जून : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भाई सावंत का निधन। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहली ५०० मेगावाट इकाई शुरू। एकीकृत अकाली दल के ६ वरिष्ठ नेता निष्कासित। उप्र में जनता पार्टी के विधायक रणजीत सिंह की हत्या।

२७ जून : अन्नाद्रमुक (जयललिता ग्रुप) की महासचिव जयललिता द्वारा अपनी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति बरखास्त। महाराष्ट्र के ३६ सदस्यीय मंत्रिमंडल में १४ नये चेहरे, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री चंद्रिका केनिया बाहर। दूरदर्शन में दिये गये साक्षात्कार में कांट-छांट बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धारा १९ का उल्लघंन घोषित।

२८ जून : कर्नाटक में जनता पार्टी का संकट दूर करने का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रयास असफल। पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा स्वर्ण मंदिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंपने से इनकार।

२९ जून : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा लोकसभा से इस्तीफा। सुभाष घीसिंग और ज्योतिबसु गोरखालैंड मसले के शांतिपूर्ण हल पर राजी।

३० जून : पूरे फरीदाबाद और तावड़ू में दोबारा मतदान के मसले पर आयोग द्वारा विचार। पी महेश्वरी यूएनआई बोर्ड आफ डाइरेक्टरर्स के चेयरमैन नियुक्त।

विदेश

१६ जून : पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर दृढ़। फ्रांस और ईरान के बीच राजनयिक संबंध पुन: कायम।

१७ जून : ब्राजील के सेनाध्यक्ष पालो राबर्टो कैमरीना बरखास्त। श्रीलंका के सात दलीय विपक्षी समूह द्वारा सरकार के चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय टीम के गठन की मांग।

१८ जून : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधियों और मुजाहिरों के बीच दंगा भड़का। विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह जिंम्बाब्वे एवं निर्गुट आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष राबर्ट मुगावे से मिलने जिम्बाब्वे पहुंचे।

१९ जून : हेती के बरखास्त जनरल हेनरी नेम्फी ने सत्ता हथियायी। पाकिस्तान को पराजित कर भारत ने प्री ओलंपिक हाकी टूर्नामेंट का खिताब जीता।

२० जून : अफगान विद्रोहियों द्वारा १२ सदस्यीय निर्वासित सरकार के गठन की घोषणा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दल अधिनियम में जनरल जिया द्वारा किये गये संशोधन अवैध घोषित। महिला प्रतियोगी नतालय जवेरेवा एवं गैब्रियेल सबातिनी विबलडन प्रतियोगिता से बाहर।

२१ जून : बर्मा की राजधानी रंगून में दंगे भड़कने के कारण दो महीनों के लिए कर्फ्यू। हेती की सशस्त्र सेना के प्रमुख लेज नेम्फी द्वारा नये मंत्रिमंडल का गठन। ग्रीक के प्रधानमंत्री पोपेंद्रू द्वारा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। कनाडा द्वारा १७ सोवियत राजनयिकों का निष्कासन।

जियाउल हक

गोर्बाचोव

२२ जून : फ्रांस के राष्ट्रपति मितरां द्वारा प्रधानमंत्री माइकेल रोकार्ड का इस्तीफा स्वीकृत।

२३ जून : आस्ट्रेलिया द्वारा फिजी विद्रोह में भारत का हाथ होने का खण्डन। तुर्की में भूस्खलन से ३०० मरे। जान मैकनरो पुरुष एकल के दूसरे दौर में आस्ट्रेलिया के केवाली मसूर से पराजित।

२४ जून : १६ देशों की इकोनामिक कमेटी आफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस की बैठक लोम (टोगो) में शुरू।

२५ जून : रूस से कनाडा के वरिष्ठ सैनिक सलाहकार का निष्कासन। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सहअध्यक्ष बेनजीर भुट्टो द्वारा अपना चुनाव अभियान शुरू।

२६ जून : मार्क फरेरा जीशान अली की जोड़ी पराजित होने के साथ ही १९८८ की विबलडन टेनिस चैम्पियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त।

२७ जून : पाकिस्तान में टैक्स चोरों के चुनाव लड़ने पर रोक। आयरलैंड के राष्ट्रपति विगदिस फिनबोगादोत्तिर तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित।

२८ जून : गोर्बाचोव द्वारा रूस में राष्ट्रपति प्रणाली का प्रस्ताव। सऊदी अरब द्वारा हज की पवित्रता भंग करने वालों का सिर धड़ से अलग करने की घोषणा।

२९ जून : बोरिस बेकर विबलडन के सेमीफाइनल में।

३० जून : अमरीकी कांग्रेस द्वारा जिया को चुनाव कराने की चेतावनी। श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलबहुल उत्तरी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाने का वादा। ■

लोक लेखा समिति

ठन गयी है सत्ता और विपक्ष में

सरकार के आय-व्यय का बेबाकी से जायजा लेनेवाली लोक लेखा समिति इन दिनों अध्यक्षविहीन और निष्क्रिय पडी है। कहते हैं, सरकार को विपक्ष के अध्यक्ष, खासकर माकपा के अमलदत्त, अब नागवार हो गये हैं। तो क्या वह अब तक की परंपरा को ताक पर रखकर इस पद पर किसी इंका सदस्य को नामजद करेगी? क्या विपक्ष ऐसा होने देगा? यह मुद्दा संसद के अगले सत्र में कौन-सा गुल खिलायेगा?

संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ सरकारी मुहिम के तहत, लगता है, अब लेखा समिति (पीएसी) की बारी आ गई है। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार, सरकारी आय-व्यय पर कड़ी निगरानी रखने वाली, यह महत्वपूर्ण समिति हफ्तों से अध्यक्ष विहीन है। फलतः समिति का काम भी पूरी तरह ठप है। एक जबरदस्त विवाद पैदा हो गया है, जिसकी चपेट में संपूर्ण विपक्ष के साथ ही शासक दल भी आ गया है। इस विवाद से न केवल लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लग गया है बल्कि संसदीय निकायों और परंपराओं के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा पैदा हो गया है।

इस विचित्र स्थिति का मुख्य कारण क्या है? कुछ भी हो, उसके मूल में अध्यक्ष बलराम जाखड़ द्वारा सारे नियमों परंपराओं को अनदेखा कर वर्तमान पीएसी अध्यक्ष और मार्क्सवादी सदस्य अमल दत्त को एक वर्ष तक और इस पद पर बने रहने की अनुमति देने से इनकार करना है। स्थिति तब और बिगड़ी जब अध्यक्ष द्वारा नामजद तेलुगु देशम के सी माधव रेड्डी ने भी इस्तीफा दे दिया। अब इस समूचे प्रकरण ने समूचे विपक्ष और शासक दल को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। सवाल उठता है, अंततः परिणाम क्या होगा? क्या अध्यक्ष जाखड़ एक बार पुनः (जैसा कि उन्होंने पिछले सत्र में उन्नीकृष्णन प्रकरण के दौरान किया) अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे बदलने को बाध्य हो जायेंगे? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह एक और पुरानी परंपरा को नजरंदाज कर शासक दल के किसी सदस्य को पीएसी अध्यक्ष बनायेंगे? दोनों ही स्थितियों में परिणाम दूरगामी होंगे।

मुद्दे का मूल : इस पूरे मुद्दे का केंद्र बिंदु अमल दत्त हैं, जिन्हें स्थापित मान्यताओं के अंतर्गत स्वतः दूसरे वर्ष भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना था। विडंबना तो यह है कि शासक दल के साथ ही इस प्रकरण में विपक्षी दल तेलुगु देशम की भूमिका भी अस्पष्ट और संदिग्ध रही है। इस भूमिका से विपक्ष को ही नहीं, पीएसी के हित को भी गहरी चोट पहुंचती है।

अमल दत्त पहली बार उनके (अध्यक्ष तथा शासक दल) तीर और प्रतिरोध का निशाना नहीं बने हैं। पिछले वर्ष पीएसी अध्यक्ष की अपनी आरंभिक नियुक्ति के समय भी उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। यद्यपि विजय अंततः उनके ही हाथ लगी। किंतु अनेक झमेलों के बीच उनकी नियुक्ति की घोषणा चार हफ्ते देर से की गई थी। अब सवाल यह कि अमल दत्त को ही क्यों इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा? फिर यह विरोध इतना जरूरी क्यों हो गया कि अध्यक्ष को दो दशक से अधिक समय से स्थापित मूल्यों और परंपराओं को भंग करने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई?

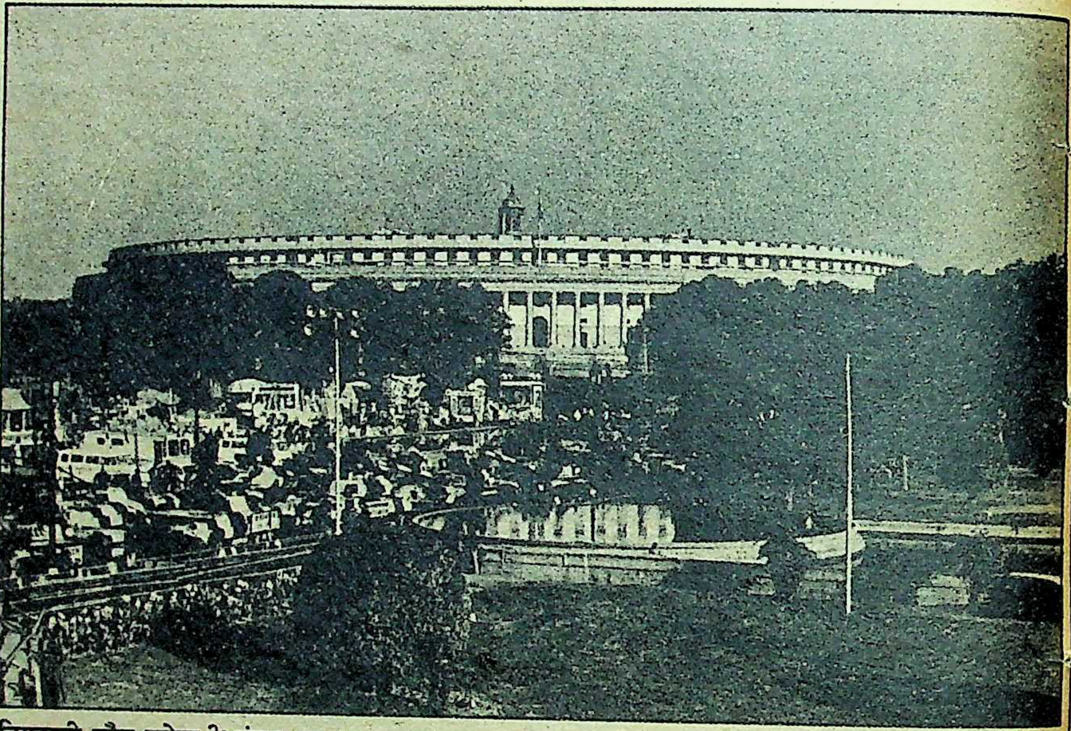

निगरानी कौन करेगा?: संसद भवन

प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के भांजे अमल दत्त अचूक शब्दबाण चलाने में बेजोड़ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें अभियान चलाने की अपार क्षमता है। घोर परिश्रम और एकनिष्ठा के अतिरिक्त अमल दत्त की रक्षा संबंधी मामलों में गहरी पैठ है। सरकार प्रायः उनके द्वारा की गई जांच-पड़ताल से समय-समय पर सांसत में पड़ती रही है। कहते हैं, दत्त की कार्यशैली में लोगों को पीएसी के बहुचर्चित पूर्व अध्यक्ष तथा मार्क्सवादी सांसद स्व ज्योतिर्मय बसु की झलक देखने को मिलती है। यही कारण है कि एक ओर सरकार उनसे भय खाती है और दूसरी ओर उनकी जड़ भी खोदती रहती है।

जहां तक पीएसी अध्यक्ष की नियुक्ति का सवाल है, वह भी ज्योतिर्मय बसु के समय की याद को ताजा करता है। जानकार सूत्रों के अनुसार श्रीमती गांधी ज्योतिर्मय बसु की संसदीय भूमिका से आतंकित और आशंकित थीं, इसीलिए उन्होंने बसु को पीएसी चेयरमैन न बनने देने के लिए असफल प्रयास किया था। कहा जाता है कि उन्होंने वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता समर मुखर्जी को बुलाकर अनुरोध किया कि वह स्वयं बसु के स्थान पर यह पद ग्रहण कर लें। मुखर्जी ने उनके अनुरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह निर्णय उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंततः बसु अध्यक्ष बन गये और श्रीमती गांधी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया।

अमल दत्त को अध्यक्ष पद से दूर रखने की सरकार की इच्छा का एक मूल कारण यह भी है कि पीएसी अध्यक्ष के रूप में उन्हें सरकारी जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार मिल जाता है। संसद की सबसे पुरानी यह वित्तीय समिति 'कंट्रोलर [illegible] आडीटर जनरल' की रिपोर्टों में उल्लिखित सरकार की अनियमितता, फिजूलखर्ची और निष्फल व्ययों के सभी मामलों की जांच-पड़ताल करती है। कभी-कभी वह स्वतंत्र रूप से भी जांच-पड़ताल करती है,

जैसाकि पिछली समिति ने जगुआर विमान के मसले को लेकर किया था। इसके अलावा पीएसी नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन पर भी नजर रखती है। वह देखती है कि निर्धारित नीति किन कारणों से बनायी गयी है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस पर अमल किस प्रकार किया जा रहा है। इस प्रकार समिति सरकार की फिजूलखर्ची और अनियमितता पर कड़ी चौकसी करती है। पीएसी के एक सदस्य ने 'माया' से बातचीत के दौरान बताया, "ऐसी स्थिति में उस सरकार को, जिसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, अमल दत्त जैसे निष्कंटक मामले की तह तक पहुंचनें वाले व्यक्ति से भयभीत हो उसका विरोध करना सरकार के लिए अस्वाभाविक नहीं।"

जगुआर रिपोर्ट: ठीक यही काम अमल दत्त ने अपने अध्यक्षता काल के दौरान बड़ी निष्ठा और लगन से किया। जांच-पड़ताल के लिए उन्होंने अपने प्रिय विषय सुरक्षा मामलों को चुना। नतीजतन अनेक सुरक्षा मामलों की गहराई से जांच हुई। बाद में समिति की रिपोर्टों में सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। मसलन समिति ने जगुआर विमान रिपोर्ट में इस विमान के चयन, अनुबंध और सौदे के कार्यान्वयन की कटु आलोचना की। कहा जाता है कि जब मामले की जांच पड़ताल की गयी तो पाया गया कि जगुआर की अपेक्षा यदि फ्रेंच विमान खरीदे जाते तो अधिक लाभकारी सिद्ध होते। जांच में पता चला कि फ्रांस ने शुरू में अस्थायी प्रबंध के अंतर्गत मिराज एफ-५ देने की पेशकश की थी। बाद में वह मिराज-२०००, जो जगुआर से कहीं बेहतर विमान माना जाता है, देने वाला था। वैसे भी जगुआर छठे दशक का विमान है और वर्तमान योजना के अंतर्गत आखिरी भारतीय जगुआर सन् २०१५ में रिटायर किया जायेगा। ऐसी सूरत में पीएसी का मानना था कि सरकार ने इस खरीदारी में १५०० करोड़ रु० पर पानी फेर दिया है।

सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कामकाज पर भी पीएसी ने तीखी टिप्पणी की। विशेषकर राडार के विकास कार्यक्रम पर। बावजूद इसके कि पिछले १६ वर्षों से इसके विकास पर काम चल रहा है, जानकार सूत्रों के अनुसार इसकी तकनीक सामान्य है। किंतु राडार का निर्माण (उत्पादन) तो दूर, अभी प्रारंभिक परीक्षण की भी नौबत नहीं आई है। इतना ही नहीं इस दौरान पीएसी ने पाया कि सरकार ने इस राडार प्रणाली की खरीदफरोख्त में करोड़ों रु० व्यय किये। पीएसी का मानना है कि यदि उचित चौकस-निगरानी हुई होती, तो यह नौबत न आती।

टैंक जांच: जहां तक प्रमुख आयुध टैंक (एमबीटी) की जांच का सवाल रहा है, पीएसी ने सरकार की रातों की नींद ही हराम कर दी। सुरक्षा मामलों के एक वरिष्ठ और जानकार सूत्र ने 'माया' को बताया, "सरकार ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया, यह इसी से जाहिर है कि जांच-पड़ताल में रुकावट डालने के लिए किसी और ने नहीं, स्वयं रक्षामंत्री ने प्रयास किया।" आरोप है कि पीएसी सदस्य जांच-पड़ताल के दौरान अवाडी (जहां एमबीटी के विकास पर काम चल रहा है) गये। वहां सदस्यों ने मुद्दे पर कई अहम और सरकार को सांसत में डालने वाले सवाल उठाये, जिनके लिखित जवाबों की अपेक्षा थी। यथासमय जवाब न मिलने पर समिति ने स्मरणपत्र भेजे। उसके जवाब की जगह डेढ़ माह बाद रक्षा मंत्री केसी पंत ने पीएसी अध्यक्ष अमल दत्त से पत्र द्वारा अनुरोध किया कि वह जांच-पड़ताल रोक दें क्योंकि संबंधित उच्चाधिकारी किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं।

राजीव सरकार को नागवार: अमल दत्त

उस समय तो मामला रुक गया। किंतु यह तय है कि दत्त अपने पद पर बरकरार रहते तो मामले को दुबारा अवश्य ही उठाते। एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी और 'हैवीवाटर' के मामले के उठाये जाने की पूरी संभावना भी रक्षा मंत्रालय और सरकार के लिए दहशत की चीज थी।

"घोटालों से भरे रक्षा मंत्रालय को दृष्टि में रखते हुए सरकार के सामने केवल यही रास्ता था कि वह दत्त को चलता करे और अधिक सुविधाजनक व्यक्ति को यह पद सौंपे।" यह टिप्पणी विपक्ष के एक जानकार नेता ने 'माया' से की।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को ही नहीं, सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों को भी १९८७-८८ की समिति (पीएसी) को संतुष्ट करने में नाकों चने चबाने पड़े। समिति के ही एक सदस्य के अनुसार "जो अधिकारीगण ऐसे मौकों पर सामान्यत: बात को घुमाफिरा कर काम निकालने के आदी थे, उन्हें समिति के दोटूक सवालों और विषय पर ही केंद्रित रहने की शर्तों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।" उदाहरण के तौर पर उन्होंने 'माया' को बताया कि अब तक प्रचलित ४५ मिनट के प्रारंभिक भाषण को दत्त ने कम कर केवल १० मिनट का कर दिया था। जाहिर है कि सभी दत्त से खार खाये हुए थे।

पीएसी के कामकाज को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए दत्त ने (जो समिति के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे) अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। सर्वप्रथम उन्होंने संबंधित प्रकाशित सामग्रियों को संकलित कर कार्यसमिति के अधिकारियों को सौंप दिया। इससे जगुआर मुद्दे की जांच-पड़ताल में बहुत सहायता प्राप्त हुई।

रिपोर्ट लिखने के तरीके में भी भारी रद्दोबदल हुआ। पुरानी रिपोर्टें छपी रिपोर्टों का संकलन मात्र थीं, जिनके उद्धरण कभी-कभी अनगिनत पृष्ठों में फैले रहते थे, जबकि समिति के अध्ययन संक्षेप में सुझाव अस्पष्ट होते थे। दत्त ने उद्धरणों का तो पूरी तरह सफाया कर दिया। केवल प्रत्यक्षदर्शियों की मूल बातों का हवाला देते हुए पाठकों को संकेत दिया कि उन्हें पता करना हो, तो वह पता कर लें। इस प्रकार उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रिपोर्टें छोटी, प्रामाणिक और पठनीय हों। 'माया' से इस विषय पर बातचीत करते हुए अमल दत्त ने कहा, "मैं चाहता था कि पाठक रिपोर्ट को एक बैठक में पूरा पढ़ ले। यद्यपि इससे समिति के पदाधिकारियों का काम काफी बढ़ गया, किंतु इससे हुई उपलब्धि की प्रशंसा हुई है। मेरा विश्वास है कि इसे भविष्य में भी अपनाया जायेगा जिससे रिपोर्ट को संबंधित लोग पढ़ेंगे और वह पुस्तकालयों तथा सांसदों की अल्मारियों में पड़ी धूल नहीं खायेंगी।"

विपक्ष की चेतावनी: अमल दत्त गत पूरे अप्रैल तक लगन और संजीदगी से कामकाज कर रहे थे। उन्हें इस बात की लेशमात्र आशंका नहीं थी कि उन्हें परंपरा के विपरीत अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जब अमल दत्त को दुबारा नामजद न करने की लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा का पता विपक्ष को लगा तो उसने दत्त की ओर से सरकार से लोहा लेने का बीड़ा उठा लिया। अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णायक कदम उठाने से पूर्व ही गत ४ मई को विपक्ष ने उन्हें एक संयुक्त पत्र लिखकर अपनी चिंता और संदेह को व्यक्त किया। विविध परंपराओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के साथ-साथ इस पत्र द्वारा विपक्ष ने अध्यक्ष को आगाह भी किया "यदि परंपराओं का उल्लंघन हुआ तो उसके दूरगामी परिणाम केवल पीएसी के कामकाज पर ही नहीं बल्कि संसदीय प्रणाली के मूलाधार, कार्यविधियों और मूल्यों पर भी पड़ेंगे।" लेकिन शासक दल के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

विपक्ष द्वारा लिखे गये इस संयुक्त पत्र में तेलुगु देशम शामिल नहीं था। अमल दत्त के अनुसार इससे भ्रम का व्यापक माहौल पैदा हुआ। इसमें एक ओर अध्यक्ष को इस बात का मौका दिया कि वह मार्क्सवादी पार्टी को दुबारा अध्यक्ष पद न दें, दूसरी ओर अध्यक्ष को माधव रेड्डी को नामजद करने का सुनहरा मौका भी दे दिया। यद्यपि रेड्डी ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया, किंतु इससे स्थिति संभल नहीं सकी। वस्तुत: इसके फलस्वरूप ही ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई है जिसके तहत पीएसी अध्यक्ष-विहीन हो गई है।

मंत्री को भी मुसीबत में डाल देती है पीएसी

वेंकटरमण

टीए पै

स्टीफन

नरसिम्हाराव

लोक लेखा समिति (पीएसी) न केवल भारतीय संसद की बल्कि उन सभी देशों की—जहां संसदीय लोकतंत्र है—सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका महत्व इस तथ्य में है कि यह सरकारी खर्चों का जायजा लेती है। इसके अभियोग अथवा सुझाव मंत्रियों तक को भारी मुसीबत में डाल सकते हैं जैसा कि कुछ समय पूर्व गनी खां चौधरी के मामले में हुआ था। पीएसी ने दर्शाया था कि मंत्री एक लीज को अवैध रूप में मंजूरी देने में समय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे और इस संबंध में अदालती मामले को जारी नहीं होने दिया जैसा कि होना चाहिए था। मंत्री गनी खां को उसके बाद गद्दी छोड़नी पड़ी थी।

भारत में पीएसी का उद्गम सन् १९२१ के 'सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेंबली' से जुड़ा हुआ है। उस समय से लेकर १९४६ तक वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के वित्तीय सदस्य इसके प्रेसाइडिंग अधिकारी हुआ करते थे। बाद में कुछ समय के लिए वित्त मंत्री स्वयं अध्यक्ष होते थे। १९५० से १९६७ तक अध्यक्ष शासक दल का हुआ करता था। विपक्षी सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाने की प्रणाली १९६७ से शुरू हुई। तब से यह परंपरा दृढ़तापूर्वक अपनायी जाती रही है। प्रत्येक अध्यक्ष लगातार दो सत्रों तक पदासीन रहें। इसका केवल एक अपवाद १९७७-७९ में देखने को मिला जब कांग्रेस-इ ने विपक्षी दल के रूप में अपनी ही पार्टी के चार लोगों—सीएम स्टीफन, पीवी नरसिम्हा राव, टीए पै और आर वेंकटरमण को इस पद पर एक-एक कर बदला। इसमें इतनी फौरी तब्दीली हुई कि इनमें से एक अध्यक्ष मात्र ४ सप्ताह तक पदासीन रहा। किंतु ऐसा परिवर्तन अपवाद रूप में ही रहा है, नियमानुसार नहीं।

मूलतः लोकसभा की समिति पीएसी में २२ सदस्य होते हैं। इसमें १५ सदस्य लोकसभा के और ७ राज्यसभा के होते हैं। यद्यपि ऐसा समझा जाता है, इसके सारे सदस्य चुने होने चाहिए। किंतु राज्यसभा परंपरा से ऐसा चुनाव नहीं करती। यह मुद्दा सर्वसम्मति से तय किया जाता है। जहां तक लोकसभा में सदस्यों के चुनाव का प्रश्न है, वह प्रायः शक्तिपरीक्षण के आधार पर होता है। वर्तमान संसद में पीएसी के चुनाव १९८५ में हुए और विपक्ष केवल ३ सदस्यों—एक तेलुगु देशम (इ अंयप्पू रेड्डी), एक जनता पार्टी (एच एम पटेल) और एक मार्क्सवादी पार्टी (अमल दत्त)—को ही भेजने में सफल रहा।

दुनिया के अन्य देशों में समिति एक बार निर्वाचित होने के बाद संसद के पूरे कार्यकाल में बरकरार रहती है, यद्यपि कुछ सदस्य बीच में बदलते रहते हैं। भारत में समिति के सदस्य हर वर्ष बदलते हैं। कभी-कभी चुनाव से बचने के लिए शासक दल, जो प्रकट कारणों से कहीं अधिक सदस्यों को भेजता है, एक विपक्षी सदस्य को शामिल करता है और सर्वसम्मति प्राप्त करता है। १९८७ मे कोई चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस-इ ने अकाली दल-लोंगोवाल के सदस्य आरएस रामूवालिया को समिति में स्थान दिलाया। इसी प्रकार १९८८ में उसने असम गण परिषद के दिनेश गोस्वामी को स्थान दिलाया।

आश्चर्य तो यह है कि समिति में सरकार और विपक्ष, दोनों के सदस्य होते हैं और उनकी शक्ति में भारी अंतर के बावजूद समिति बेहद तालमेल और सौहार्द के साथ काम करती है। न तो जांच के लिए चुने गये विषय पर संघर्ष होता है और न जांच के तरीकों पर। फैसले भी सर्वसम्मति से होते हैं। जैसा अमल दत्त का कहना है, "पीएसी में यद्यपि शासक दल के अधिक संसद-सदस्य शामिल होते हैं, फिर भी जब जांच-पड़ताल का समय आता है तो वे अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपने विपक्षी साथियों से कम उत्सुक नजर नहीं आते।"

समिति का क्षेत्र और अधिकार व्यापक है। पीएसी परंपरानुसार कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल (सीएजी) के लेखा (आडिट) आपत्तियों, जोकि संसद में विशेष रिपोर्ट के रूप में पेश होते हैं, के आधार पर कार्य शुरू करती है। वैसे यह स्वतंत्र रूप में भी जांच कार्य कर सकती है। मसलन हाल के जगुआर विमान मामले की जांच। पीएसी नीतियों, उनके निर्धारण और कार्यान्वयन को भी देखती-परखती है। वह असंगतियों/खामियों की ओर संकेत करती है और सुधारात्मक कदमों को सुझाव देती है।

इतने व्यापक क्षेत्र व अधिकार के बावजूद पीएसी कम समय होने और विभागों से तमाम जरूरी रिकार्ड न मिल पाने के कारण इंसाफ नहीं कर पाती। यह समस्या कितनी गंभीर है, यह इसी से स्पष्ट है कि गत वर्ष पीएसी ने ६९ आपत्तियों को अपने हाथ में लिया था। इनमें से केवल ३ की ही पीएसी व्यापक जांच कर पायी थी, वह भी रात दिन एक करने के बाद। वैसे पीएसी का पिछला रिकार्ड मात्र २ मामलों तक ही सीमित रहा है।

मूलतः यह समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि संसद का अधिवेशन मात्र छह महीने ही चलता है। बीच के समय में समिति दो बार से अधिक नहीं मिल पाती। समय की इस कमी से समिति को तीन अलग समितियों में बांटने का प्रस्ताव है। सदस्यों को इस बात की गंभीर चिंता है कि एक तो समय कम है, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष मसले को निपटाने में देरी कर रहे हैं। इससे समिति का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

वर्षों के अंतराल में पीएसी ने ये परंपराएं और मानदंड विकसित किये हैं: १- अध्यक्ष पद के लिए विपक्षी सदस्य को चुनना, २- अध्यक्ष पद के लिए बारी-बारी से पार्टियों का चुनाव, संसद में उनकी शक्ति और स्थिति के अनुसार करना। ३- अध्यक्ष के लिए दो वर्ष का सत्र।

इस अंतिम परंपरा को ही लोकसभा अध्यक्ष ने भंग करने का फैसला किया जिसका विपक्ष ने अपनी समूची ताकत से मुकाबला करने का फैसला किया है। जीत किसकी होगी? यह तो समय ही बतायेगा।

—रंजना कक्कड़

माकपा और देशम : मजेदार बात तो यह है कि यदि अध्यक्ष द्वारा अमल दत्त के मार्ग में रुकावट डालने का यह पहला अवसर नहीं है तो तेलुगु देशम द्वारा निभायी गयी यह अहम भूमिका भी पहली नहीं है। गत वर्ष भी जब अध्यक्ष पद का मसला उभरा था तो तेलुगु देशम ने, बावजूद इसके कि पिछले अध्यक्ष (इयप्पू रेड्डी) उनकी अपनी पार्टी के ही थे, न केवल इसके लिए अपना दावा पेश किया था बल्कि प्रचार भी किया था। इसे विपक्ष के जबर्दस्त विरोध के बाद ही छोड़ा गया था। विपक्ष का मानना था कि परंपरानुसार यह पद संसद में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मिलना चाहिए था। दूसरे, एनटीआर ने भी अपने सांसदों पर लगाम लगायी थी। इसके बाद तेलुगु देशम सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर घोषित किया कि पेशकश होने पर भी वह पद कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष के पास अमल दत्त की नियुक्ति के अलावा और कोई चारा ही न था।

हालात इस बार भी लगभग वैसे ही रहे हैं। तेलुगु देशम ने एक बार फिर दावा पेश किया जिसे पार्टी ने काफी जन असंतोष, आरोप-प्रत्यारोपों और एनटीआर की कथित फटकार के बाद वापस लिया। किंतु यह दावा वापस लेने में एक बड़ा फर्क यह था कि इस साल तेलुगु देशम ने लोकसभा अध्यक्ष को विधिवत पत्र लिखकर अपनी अस्वीकृति नहीं जतायी। "माधव रेड्डी ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपनी अनिच्छा जाहिर की! नतीजतन अध्यक्ष रेड्डी को नामजद करने का मौका पा गये। यदि तेलुगु देशम ने पहले ही अध्यक्ष को लिखित सूचना दी होती तो वह मुझे पीएसी की अध्यक्षता से वंचित नहीं कर पाते।" अमल दत्त ने 'माया को बताया।

दिल्ली के सत्ता गलियारों में तेलुगु देशम (माधव रेड्डी) द्वारा अध्यक्ष को पत्र न लिखे जाने के कारणों को लेकर तरह-तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जाता है कि पिछले वर्ष अध्यक्ष ने माधव रेड्डी को सब कुछ लिखकर देने के कारण अपनी पार्टी का अहित करने और अपने (अध्यक्ष के) हाथ बांध देने के लिए लानत-मलामत की थी। दुर्भाग्यवश, तेलुगु देशम की यह भूल न केवल विपक्ष को भारी पड़ी है बल्कि स्वयं लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति पर भी अनावश्यक रूप से आंच आई है।

माधव रेड्डी का मामला तो और विचित्र है। संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में उनके कामकाज की जिम्मेदारी इतनी अधिक है कि पीएसी सदस्य का कार्य करना उनके लिए मुश्किल था, अध्यक्ष की बात तो दूर है। फिर भी अध्यक्ष ने उन्हें नामज़द करना उचित समझा और रेड्डी ने बेमन से उसे अस्वीकार कर दिया।

रेड्डी के रोष का कारण यह भी है कि उन्हें विपक्षी योजना की जानकारी से अलग रखा गया था, विशेषकर तब जब मार्क्सवादी नेता वासुदेव आचार्य सदन में उनके बगल में बैठते हैं। साथ ही यह भी कि जब सात विपक्षी दलों ने अध्यक्ष बलराम जाखड़ को पत्र लिखा तो उसमें तेलुगु देशम को शामिल नहीं किया गया। एक रुष्ट मार्क्सवादी सांसद का कहना है, "तेलुगु देशम को शामिल करने या उनसे अनुरोध करने का कोई प्रश्न ही कहां उठता था ? क्योंकि माधव रेड्डी ने अमल दत्त से इस मसले पर हुए विचार-विमर्श के दौरान दृढ़तापूर्वक यह मत प्रकट किया था कि अध्यक्ष को समिति के किसी भी सदस्य और विपक्षी नेता को अध्यक्ष नामजद करने का अधिकार था। उन्होंने तो इस विचार को भी दरकिनार किया था कि परंपरानुसार अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष होना चाहिए।"

यह सही है कि तेलुगु देशम सिद्धांत रूप में एक सदस्य को एक ही साल का कार्यकाल देता आया है। किंतु अयप्पू रेड्डी के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने सहर्ष इस सिद्धांत को ताक पर रख उन्हें दूसरे साल भी अध्यक्ष बने रहने दिया था। इसलिए उनकी वर्तमान मान्यता कि अध्यक्ष पद बारी-बारी से प्रति वर्ष बदले, तर्कसंगत नहीं जान पड़ती।

परम्परा की अवहेलना : बलराम जाखड़

यदि बारी-बारी से बदलने का सिद्धांत लागू किया जाता है तो भी यह पद तेलुगु देशम को नहीं बल्कि सही अर्थों में जनता पार्टी को मिलना चाहिए। १९८५ के चुनाव में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के पश्चात पीएसी में शामिल होने वाली जनता पार्टी को अभी तक अध्यक्ष पद प्राप्त नहीं हुआ है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मार्क्सवादी पार्टी के प्रति तेलुगु देशम के वर्तमान रोष और असहयोग का कारण कदाचित पिछला राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में मार्क्सवादी पार्टी ने वादाखिलाफी कर तेलुगु देशम उम्मीदवारों को समर्थन नहीं दिया था। नतीजतन तेलुगु देशम को राज्यसभा में अपने दूसरे स्थान को खोना पड़ा था। जवाब में मार्क्सवादियों का कहना है, "तेलुगु देशम के लोग शायद १९८४ के वे दिन भूल गये हैं जब श्रीमती गांधी ने बड़ी चतुराई से एनटीआर को अपदस्थ कर दिया था और उनको पुन: पदारूढ़ कराने में हमने ही निर्णायक भूमिका निभायी थी।"

एक तीर दो शिकार : नि:संदेह दाल में कुछ काला है। किंतु इससे विपक्षी हितों और स्वयं पीएसी की जो हानि हुई है, वह अपूरणीय है। इस पूरे मामलें में किसी की जीत हुई है तो वह शासक दल कांग्रेस की है। उसकी रणनीति न केवल संकट में डालने वाले अध्यक्ष अमल दत्त को हटाने में सफल रही है बल्कि स्वय विपक्षी किले में भी उसने सफलतापूर्वक सेंध मारी की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने एक बार फिर परंपराओं की अवज्ञा कर लोकतांत्रिक संस्थानों, मानदंडों और मूल्यों के प्रति अपनी उपेक्षा और निरादर का खुलेआम प्रदर्शन किया है। प्रश्न यह है, इस सब का नतीजा क्या होगा ? वर्तमान स्थिति में इस मसले पर एकजुट विपक्ष इसको खामोशी से बर्दाश्त न करने के लिए कटिबद्ध नजर आता है। इसके तहत गत ३१ मई को लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने पत्र में विपक्ष ने पुन: अनुरोध किया है, "विपक्षी दलों द्वारा भेजी गयी याचिका पर ध्यान दें, अन्य वित्तीय समितियों में प्रचलित परंपरा को मद्देनजर रख पीएसी अध्यक्ष को दूसरा कार्यकाल प्रदान करें और इसके अंतर्गत लोकसभा के मार्क्सवादी सांसद अमल दत्त को पुन: नामजद करें।" प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अध्यक्ष जाखड़ इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। अत: पत्र पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उनकी वापसी पर ही संभव होगी।

अविश्वास की तैयारी : इस संबंध में विकल्प सीमित है। यदि विवेकपूर्ण समझदारी बनी रही है तो अध्यक्ष टकराव का रुख अपनाने की जगह पुनर्विचार कर और अपने निर्णय को वापस लेकर, परंपरानुसार अमल दत्त को पुन: नामजद करेंगे। वैसी स्थिति में यदि एकमात्र क्षति होगी तो बहुमूल्य समय की जो पीएसी के पास वैसे ही कम होता है।

बहरहाल, यदि अध्यक्ष विपक्ष के किसी प्रकार के सहयोग की गैरमौजूदगी में तथा स्थापित मानदंडों के विपरीत शासक दल के किसी सदस्य को नामजद करते हैं तो संसद के आगामी मानसून सत्र में भारी कुहराम मचने की संभावना है। जानकार सूत्रों का कहना है कि तब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

यद्यपि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इसी प्रकार का प्रस्ताव गत वर्ष भी लाया गया था (जो सचमुच अनूठा था) किंतु इस बात के संकेत हैं कि इस बार यह (अविश्वास प्रस्ताव) अत्यधिक कड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष बलराम जाखड़ पर व्यक्तिगत रूप से, निजी प्रकार के अनेक आरोपों की बौछार करके, प्रहार करने में हिचकिचायेगा नहीं। एक जानकार सूत्र के अनुसार दरअसल जाखड़ अमल दत्त की जांच-पड़ताल की आदत से खुद चौकन्ने हैं क्योंकि कहीं उन्होंने (दत्त ने) जांच का जाल संसद के अगले बजट तक फैला दिया तो यह उनके लिए सांसत बन सकता है। यह तो समय ही बतायेगा कि अंतिम नतीजा क्या होगा ? किंतु इस बीच व्यापक कहा-सुनी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला सदन में चल सकता है।

—रंजना कक्कड़

साक्षात्कार/एमएस सथ्यू

'चोली-दामन' हिंदू और सिखों के आपसी प्रेम की कथा है

पंजाब, आतंकवाद और नृशंस हत्याएं-ये आज कुछ ऐसे विषय हैं, जिसे राजनेता, पुलिस तथा दूसरे अपने-अपने ढंग से भुना रहे हैं, तो फिल्मकार कैसे पीछे रहते? पंजाब की वास्तविक स्थिति को 'दूरदर्शन' के परदे पर दिखाने का बीड़ा उठाया है, प्रसिद्ध फिल्मकार एमएस सथ्यू ने 'चोली दामन' के नाम से। जो कभी 'गर्म हवा', 'सूखा' और 'कहां-कहां से गुजर गया' जैसी संवेदनशील फिल्में बनाकर चर्चा के विषय रहे हैं। 'चोली दामन' में पंजाब में आज आतंकवादियों द्वारा मचायी गयी त्राहि-त्राहि के बाद की सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया गया है।

प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार कर्तार सिंह 'दुग्गल' ने इसकी पटकथा बनायी है। उन्होंने इसमें यह दिखलाने की कोशिश की है कि आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा हिंदू और सिखों में चाहे जितनी फूट डाली जाये, उन्हें अलग करने की कोशिश की जाये। लेकिन उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह साथ तो 'चोली और दामन' का है।

एमएस सथ्यू इस सीरियल की शूटिंग गुड़गांव (हरियाणा) तथा पंजाब में होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, नांगल तथा जालंधर में कर रहे हैं। छह एपीसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जून महीने तक अन्य छह एपीसोड भी पूरे हो जायेंगे। निर्माता कुक्कू माथुर जुलाई तक इसे राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाने की आशा बांधे हुए हैं।

'चोली दामन' की कहानी दो परिवारों (हिंदू और सिख) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जालंधर के एक इलाके में पड़ोसी हैं। गुरुमुख सिंह (राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भूतपूर्व निदेशक मोहन महर्षि) और लाला रामलाल (श्याम अरोरा) ने देश के विभाजन से लेकर अब तक हर सुख-दुख को एक साथ सहा था, लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश में अलगाववादी संदेह की चिनगारी यहां भी अपनी तपिश दिखाती है।

गुरुमुख का बेटा मंजीत (दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र मंजीत सिंह) और लाला राम लाल की बेटी प्रीत ('अंकुश' की अभिनेत्री निशा सिंह) का आपस में वर्षों से प्रेम चल रहा है, जिसे दोनों परिवारों द्वारा इजाजत भी मिल चुकी होती है, लेकिन सांप्रदायिकता की आंच इस रिश्ते पर भी पड़ती है। संदेह और अविश्वास के माहौल में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, जिससे इस प्रेमी युगल का सपना टूटता प्रतीत होता है, लेकिन अंततः विजय भाईचारे, विश्वास और अटूट बंधनों की होती है।

सीरियल का मुख्य पक्ष मानवीय भावनाएं और सहअस्तित्व का प्रभाव है। सीरियल में लाला राम लाल की पत्नी की भूमिका में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग की अध्यक्ष रानी बलबीर कौर हैं। सीरियल का पार्श्वसंगीत (गुरुवाणी पर आधारित) दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र के पंडित अमरनाथ ने तैयार किया है।

'चोली दामन' के अन्य पहलुओं को समझने के लिए गत दिनों 'माया' के प्रतिनिधि ने बंबई आये एमएस सथ्यू से बातचीत की। प्रस्तुत हैं, मुख्य अंश:

माया: पंजाब की वास्तविकता को 'दूरदर्शन' पर दिखा पाना संभव है?

सथ्यू: क्यों नहीं? हमें वहां की राजनीति, सरकार की कार्रवाई इत्यादि से कुछ लेना-देना नहीं है, बस वहां के सामाजिक माहौल की सच्ची तस्वीर दिखानी है। सच कहें, तो पिछले तीन वर्षों में पंजाब में जो कुछ सख्ती हुई है, उसकी एक गलत तस्वीर दुनिया के सम्मुख बनी है, जबकि सचाई यह नहीं है। आज भी हिंदू-सिखों में वहां प्रेम-सद्भाव पूर्ववत बरकरार है, फतवा तो केवल आतंकवादी दे रहे हैं।

माया: हत्या, मारकाट, खौफ, डर, वहशीपन वहां नहीं है, यह मानना तो बेमानी होगा।

सथ्यू: लेकिन इसका असर सांप्रदायिकता के कारण नहीं है, हम यही दिखाना चाहते हैं। आज भी पंजाब के गांवों में हिंदू-सिख उसी एकता-भाईचारे के साथ रह रहे हैं। यह हमने खुद अपनी आंखों से देखा और कैमरे में कैद किया।

माया: हुई कभी किसी आतंकवादी से भेंट?

सथ्यू: जरूर! लेकिन उन्हें देखकर, उनसे मिलकर दुख ही हुआ कि किस प्रकार उनका 'ब्रेनवाश' करके उन्हें इस राह पर ढकेला गया है। सभी दिग्भ्रमित, बेरोजगार युवक हैं, जिन्हें सांप्रदायिकता या धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। क्या आपने इतने वर्षों के दौरान पंजाब में चोर, बदमाश, डाकू और तस्करों की घटनाएं सुनीं?—नहीं। क्योंकि सभी कुछ 'आतंकवादी' के नाम की आड़ में चल रहा है। हमारे सीरियल का मुख्य उद्देश्य इसी को उजागर करना है।

क्या सीरियल लोकप्रिय होगा?: 'चोली दामन' का एक तनावभरा दृश्य

प्रेम संबंधों पर आतंकवाद की छाया: 'चोली दामन' का एक दृश्य

माया : गांवों में शूटिंग होने से सीरियल कुछ 'तथ्यों को जरूर समेट पायेगा।

सथ्यू : आपको मैं एक 'रहस्य' बताऊं? आज तक आनंदपुर साहिब के अंदर कोई कैमरा कुछ 'शूट' नहीं कर पाया है, लेकिन 'चोली दामन' में १० मिनट तक का दृश्य इसमें है। हुआ यों कि एक दिन तड़के ही हम अपने कैमरामैन के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचे और 'शूट' करने की तैयारी करने लगे। तभी चार युवकों (आतंकवादियों) ने हमें आ घेरा और आपत्ति की। मैं उन्हें बेटा-बेटा कहकर दूर ले जाने में सफल हुआ, तब तक हमारे 'आन' कैमरे ने अपना काम कर लिया। वे हमें उस रात वहीं रोककर अपने 'नेता' के समक्ष पेश करनेवाले थे, लेकिन हम झांसा देकर चंपत हो गये।

माया : क्या इससे प्रतीत नहीं होता कि आप भी सहमे हुए थे?

सथ्यू :...हां-थोड़ा डर तो था ही।

माया : आप वैसे १९५२ से फिल्म उद्योग में हैं, लेकिन 'गर्म हवा' के अलावा आपने कोई चर्चा योग्य कृति नहीं दी?

सथ्यू : इसका दोषी मैं नहीं मेरा भाग्य ही है। 'गर्म हवा' (जनवरी '७४) जब आयी, तब आर्ट फिल्मों का वह माहौल नहीं बन पाया था। फिल्म व्यावसायिक स्तर पर नहीं चल पायी। १९८३ में 'सूखा' (कन्नड़ में 'बटा' नाम से डब की गयी) का भी यही हाल हुआ। अनिल कपूर को पहली बार मौका देकर 'कहां-कहां से गुजर गया' बनायी, तो वह फिल्म उद्योग की हड़ताल, बंबई के केवल एक मिनी थियेटर आकाशवाणी में रिलीज होने के कारण पिट गयी। बस यों समझिए 'प्लस-माइनस' के इसी चक्कर में रहा हूं। लेकिन अब निर्देशन के अच्छे अवसर से खुश हूं।

—प्रस्तुति : अनीता

मिर्जा गालिब

जैसा व्यक्तित्व वैसी प्रस्तुति

सक्षम निर्देशन कुशल अभिनय : निर्देशक गुलजार, नसीरुद्दीनशाह व तन्वी आजमी

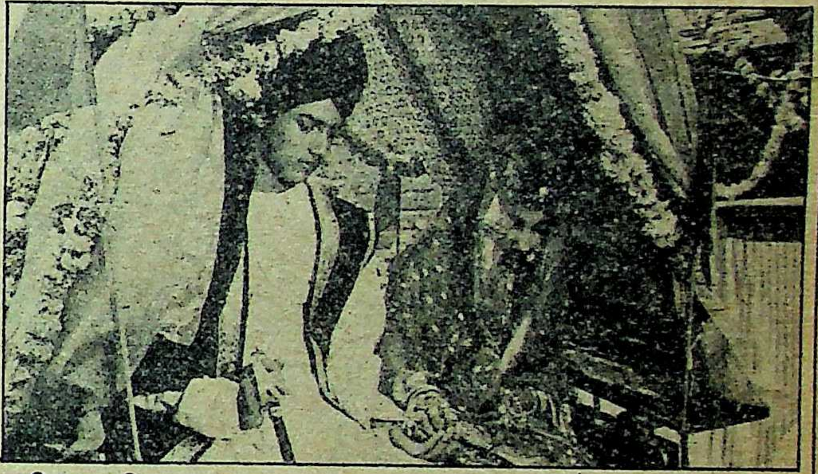

गालिब का विवाह

दूरदर्शन ने कुछ समय पहले एक नीतिगत फैसले के अंतर्गत भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाने की पहल की और धार्मिक महाकाव्यों, गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कथाओं एवं उसके वीरों की 'छोटे परदे' पर लाइन-सी लग गयी। कलाम सुनानेवाले कलम के सिपाहियों की पंक्ति में 'संत कबीर,' 'बहादुरशाह जफर' और 'अमीर खुसरो' के बाद शीघ्र ही 'मिर्जा गालिब' साहब का आगमन भी अब दूरदर्शन पर होने वाला है। मिर्जा गालिब का 'भारतीय साहित्य' में अत्यंत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी शेरो-शायरी, गजल, रुबाइयों से उर्दू और हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया। उनके कलामों की कशिश उन्हें दूसरे शायरों से अलहदा खड़ी करती है। इस संवेदनशील शायर की जीवन कथा को उसी रूहानी लहजे में दूरदर्शन तक पहुंचाना कोई आसान बात तो थी नहीं, इसके लिए जरूरी था कि इसे गढ़ने वाला भी वे सारी खूबियां रखता हो। गुलजार जैसे निर्देशक से बढ़कर और कौन हो सकता था? गुलजार की 'दूरदर्शन' पर यह दूसरी पारी है। गत दिनों अंधेरी के फिल्मालय स्टूडियो के विशाल सेट पर वह इस सीरियल के सातवें एपिसोड की शूटिंग में व्यस्त थे।

भूमिकाओं में कौन? : 'मिर्जा गालिब' की टाइटिल भूमिका में हैं—नसीरुद्दीन शाह। 'छोटे परदे' से दूर रहनेवाले नसीर ने काफी मनव्वल के बाद गुलजार के कहने पर यह भूमिका स्वीकारी है। वह इस रोल में कितनी जान फूंक सकते हैं, यह तो सीरियल ही बतायेगा, लेकिन गुलजार-नसीर गठबंधन निश्चित रूप से 'श्रेष्ठ' होना चाहिए। नसीर की पत्नी की भूमिका में हैं, तन्वी किरण-आजमी, जबकि अन्य भूमिकाएं निभायेंगे, अमजद खान व जावेद खान (दोनों फकीर), परीक्षित साहनी एवं समीर कक्कड़ (गालिब के भाई), शफी इनामदार (शायर जौक), इफ़्तिखार (गालिब के ससुर) और राजेंद्र गुप्ता (दोस्त)।

१८३० से १८६२ तक के काल की इस कहानी में गालिब के बचपन से मरते दम की घटनाओं को गूंथा गया है। वास्तविकता यही है कि मिर्जा गालिब की प्रतिभा को जिंदगी भर सम्मान नहीं मिला। मिर्जा गालिब (जिनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान था) बहादुरशाह जफर के दरबार में अपना दरबारी शायर का सम्मान पाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन जफर से भी पूर्व अकबरशाह के जामने से दरबारी शायर रहे 'जौक साहब' हर बार तिकड़म द्वारा उन्हें पछाड़ते रहे।

शराब और जुआ में हमेशा डूबे रहने वाले गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन बचपन गुजारा दिल्ली की काथी गली में। विवाह के बाद वह अपने ससुर के यहां घरजमाई बनकर रहे, लेकिन पुश्तैनी पेंशन के लिए अंग्रेजों से उनकी लडाई हमेशा जारी रही। इस पेंशन का फैसला पाने में वर्षों हुई देरी पर वह गवर्नर जनरल मैटकाफ से मिलने कलकत्ता गये। अपनी शेरो-शायरी का खजाना लुटाते हुए वह वर्षों बाद कलकत्ता पहुंचे। रास्ते में वह अपनी पूर्व चहेती लखनऊ की कोठेवाली नवाब जान से भी मिले। इसके अलावा वह आगरा, फैजाबाद, अवध, बनारस होते हुए तीन साल में कलकत्ता पहुंचे थे, जहां गवर्नर जनरल ने कलकत्ता के शिक्षा माध्यम का मुखर विरोध करने पर गालिब की बात ही नहीं ठुकराई, बल्कि जेल की सजा भी सुनायी। गालिब साहब का कहना था कि यह अनिवार्यता हटा दी जाये कि हिंदू ही हिंदी और मुस्लिम ही उर्दू पढ़ा सकेंगे।

सीरियल के निर्माता जय सिंह इसे जिस प्रकार भव्य स्वरूप दे रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह कोई कोताही नहीं चाहते। 'मिर्जा गालिब' की शूटिंग बंबई के अलावा बनारस और होशंगाबाद में भी होगी। सीरियल का शोध कार्य कैफी आजमी का है, जबकि निर्देशन के अलावा कहानी, संवाद और पटकथा गुलजार की है। गालिब के नगमों को स्वर और संगीत जगजीत-चित्रा सिंह दे रहे हैं।

—अनिता

पति-निंदा रस

खाली वक्त में महिलाएं क्या करती हैं, सौंदर्य की देखभाल, पड़ोसी से प्रेम, पति-निंदा या राजनीति पर बहस? मेरा खयाल है—इनमें से सबसे लोकप्रिय समयबिताऊ दिलचस्प काम है पति-निंदा। हिंदुस्तान में अभी वह हाल तो नहीं कि ठीक सात साल बाद यह निंदा और ब्याज-स्तुति का सिलसिला शुरू हो जाये जैसा कि हालीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। पर ग्यारह से सत्रह साल पुरानी शादी वाले पति सावधान! आप दफ्तर में अगर यह सोच कर बैठे हैं कि इस वक्त पत्नी आप द्वारा निर्मित ठंडे कमरे में पड़ी सो रही होगी या कुछ मीठी-मींठी महिला-पत्रिकाएं पलट रही होगी, तो आप भूल कर रहे हैं। इस वक्त आपकी पत्नी फोन पर या प्रत्यक्ष, सहेलियों से या पड़ोसिनों से या मंथरा महरी से आपके बारे में गंभीर मंत्रणा कर रही होगी। बाकायदा स्पर्धा चल रही होगी सबमें कि कौन कितनी शिकायत कर सकती है। मेरा खयाल है पुरुषों को चंदा कर विवाह-सलाहकार समिति का एक उड़नदस्ता गठित कर लेना चाहिए जो उन्हें पत्नियों की लोकेशन और वोकेशन बताता रहे।

समर्पिताएं इस वक्त सोच रही होंगी कि भला अपने देवता-सम पति की बुराई भी कोई कर सकता है, पर वे ध्यान दें। पति नाम के जीव के साथ कुछ साल गुजार कर देख लें, फिर उनका मन करेगा अपने साथी को यों लीपापोती वाली नजर से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें।

जिस वक्त सरकारी अफसरान चुनाव के कारण बीस-बीस घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, उनकी पत्नियां आपस में मिल-बैठ कर यही कर रही थीं। अपने-अपने पति की आचरण-पुस्तिका लिख रही थीं। कुछ देर तो खूब हमारे वो, हमारे वो हुआ, पर जैसे ही मैंने पटरी बदलकर कहा, "मेरे पति में यह बड़ी बुराई है कि उन्हें मित्र-शत्रु की पहचान नहीं," सब-की-सब अपनी सत्रह साला ऊब, खीझ और गुस्सा ले कर सामने आ गयीं। शिकायतों का पिटारा खुल गया।

"मेरे शौहर में यह बड़ी खराबी है कि सौ बार सुनाया मजाक फिर-फिर सुनायेंगे और हर बार उम्मीद रखेंगें कि मैं हंसूं। एक मजाक पर कहीं बार-बार हंसा जा सकता है।"

"मेरे पति हंसते, तो क्या बात थी! वह तो बस सूरमा-दफ्तरी हैं। दफ्तर से आकर दफ्तर के ही किस्से ले बैठते हैं। चाहे चाय पियो, चाहे खाना खाओ, उनका फाइल-युद्ध सुनना ही पड़ता है। अवस्थी ने यह लिखा तो उन्होंने यह कहा, सक्सेना ने यह जड़ दिया, तो उन्होंने ये टिप्पणी मारी। भगवान बचाये इनके फाइल-प्रेम से। इतना प्रेम तो मुझे भी नहीं करते जितना अपनी फाइलों को। मुझे तो इनके कपड़ों तक से फाइलों की बू आती है।"

"मेरे पति अपने को घर में भी अफसर समझते हैं। अगर मैं कोई समस्या बताती हूं, तो कहते हैं, ठहर जाओ, मैं तुम्हें बाद में 'डील' करूंगा।"

गरज यह कि जितने किस्म के पति, उतने किस्म की शिकायतें थीं। क्योंकि इस बातचीत की कप्तानी मैं कर रही थी, यह बड़ा जरूरी था कि पति-पत्नी संबंधों को वापस मझधार से किनारे की ओर ले जाया जाये।

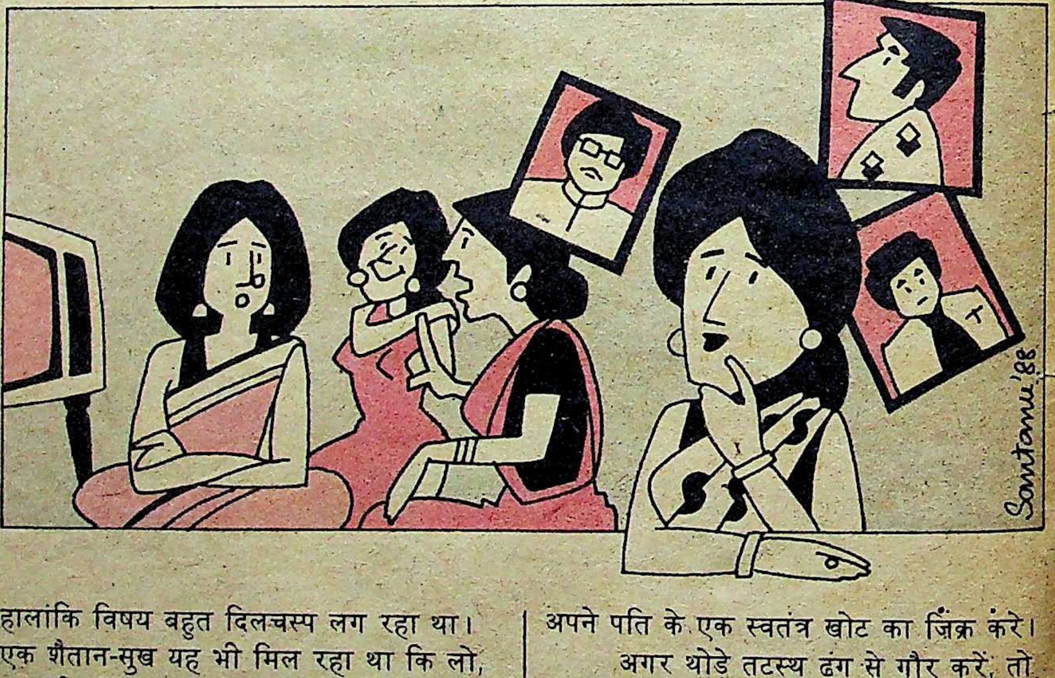

हालांकि विषय बहुत दिलचस्प लग रहा था। एक शैतान-सुख यह भी मिल रहा था कि लो, सब की हालत एक सी है। सबको किसी-न-किसी बात से असंतोष है। सब एक बेहतर तालमेल चाहती हैं।

मैंने कहा "जो हो, मेरे पति सरल बहुत हैं, जिस-तिस पर विश्वास कर लेंगे।"

"मेरे पति इतने सीधे हैं कि उन्हें रेखा, जयाप्रदा में कोई फर्क नजर नहीं आता। हर बार जयाप्रदा को रेखा और रेखा को जयाप्रदा समझ जाते हैं।"

"नौकर कोई भी दाल बना दे, अगर मैं कह दूं कि यह अरहर की दाल है, तो वह अरहर की दाल समझ कर ही खा लेते हैं। इतने सीधे हैं वह।"

"इतना सीधापन भी किस काम का? ऐसा आदमी घर से निकला नहीं कि खतरा पैदा हुआ। कोई भी फायदा उठा ले।" एक महिला ने कहा।

"सच्ची, मैं तो इन्हें टूर पर भेजते भी डरती हूं। आजकल जो खराब नहीं, उसे भी लोग खराब कर देते हैं। घर की सुख-शांति बरबाद हो जाती है।"

"बिलकुल ठीक कह रही हो। मैं लाख समझाऊं कि दुनिया बहुत बुरी है, पर मेरे पति समझते ही नहीं। हर कोई अच्छा लगता है उन्हें।"

कमोबेश यही शिकायत मुझे भी रहती है, पर हैरानी मुझे यही है कि पत्नियां यह मानती हैं कि उनके पति के दोष भी उनके गुणों में से निकलते हैं। क़िसी भी महिला में इतना साहस नहीं था कि वह बिना गुण का बखान किये अपने पति के एक स्वतंत्र खोट का ज़िक्र करे।

अगर थोड़े तटस्थ ढंग से गौर करें, तो हम पायेंगे कि यह निंदा-स्तुति और आलोचना इतनी बुरी नहीं है कि इनसे संबंधों में कोई बड़ा जलजला आये। होता यह है कि जब हम किसी के बहुत करीब रहते हैं, तो उसका एक आदर्श रूमानी रूप अपने मस्तिष्क में निर्मित करते हैं। कुछ समय बाद आदर्शवादी रूमानियत थोड़ी कम हो जाती है, आंखों का नंबर थोड़ा ठीक होने लगता है और यथार्थ का चश्मा चढ़ने के कारण एकदम साफ दिखने लगता है, पति का कटखनापन, पति की दी हुई कैद, कोलाहल और कम्बख्ती, अपना और पति का दृष्टि-भेद, सहमति की असहमति और अपनी आजादी का अपहरण। इस लिहाज से विवाह धीरे-धीरे होश में लाने वाली संस्था का नाम है। जिस स्त्री का व्यक्तित्व जितना कम स्वतंत्र है, उसे उतनी देर में होश आयेगा और आयेगा जरूर यह तय है।

—ममता कालिया

जान लेवा नर्स

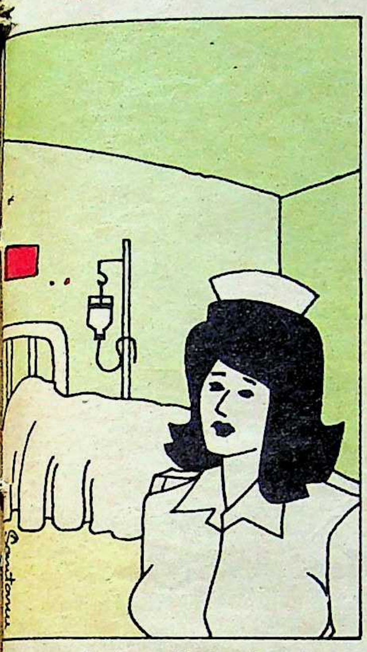

अस्पतालों में नर्सों की रोगियों की तीमारदारी में खास भूमिका होती है। कभी-कभी तो देखा गया है कि नर्सें डाक्टरों के भी कान काट देती हैं। डाक्टर रहें या नहीं, पूरे वार्ड का जिम्मा उन्हीं पर रहता है। वे इतने प्यार-दुलार के साथ मरीजों की सेवा करती हैं कि उन्हें सिस्टर की संज्ञा दी गयी है। लेकिन अगर किसी नर्स की वजह से मरीज मरने लगें, तो हैरत तो होगी ही। वाशिंगटन स्थित प्रिंस जार्ज अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में तैनात ३० वर्षीय जेन वोल्डिंग एक ऐसी नर्स है, जिसके कक्ष में भरती होने वाले कई मरीजों की मृत्यु दिल के दौरे से हो गयी। जबकि दूसरी नर्सों के मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता। ताज्जुब तो यह है कि मृतकों की हत्या का न तो कोई सबूत मिलता है और न कोई चमश्दीद गवाह। जेन के वार्ड में जनवरी १९८५ से मार्च तक ५९ मरीजों को कुल १११ बार दिल के दौरे पड़े। यों इन मरीजों की देखभाल के लिए कुल ३८ नर्सें तैनात थीं, लेकिन ५२ फीसदी दिल के दौरे जेन की रात की ड्यूटी में पड़े थे। जेन मरीजों को कोई ऐसी दवा देती है या उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी खास बात है, जिससे मरीजों को दिल के दौरे पड़ते हैं, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन जेन के ऊपर फिलहाल तीन हत्याओं और सात हत्याओं की कोशिशों के लिए मुकदमे चल रहे हैं।

किस्मत कुतिया की

यह कौन नहीं चाहता कि उसके लड़के-लड़की की शादी या गौना धूमधाम से हो। यह दूसरी बात है कि अधिकांश लोग तो दो वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते, बच्चों की शादी विवाह या गौने की क्या सोचें? यदि किसी तरह कतर ब्योंत कर शादी कर दी, तो वरपक्ष के नखरे बरदाश्त करते ही दिन गुजरते हैं। ऊपर वाले की भी क्या लीला है कि जिसे वह कोई संतान नहीं देता, उसे अकूत धन-संपत्ति दे देता है। अब वे खर्च करें, तो किस पर? बहुतेरे लोग तो कुत्ते-बिल्लियों को ही गोद ले लेते हैं। उन्हीं का जन्म-दिन मनाकर उनकी शादी वगैरह कर अपने मन की लालसा पूर्ण करते हैं। लखनऊ के निगोहा गांव की एक ऐसी ही बुढ़िया जो अपनी लाडली कुतिया पर अपनी जान न्यौछावर करती है, ने दो महीने पहले उसकी शादी की थी और फिर बड़ी धूमधाम से उसका गौना किया। उसने गौने की बाकायदा सभी रस्में भी पूरी कीं। सैकड़ों लोग इस कुकर भोज में शामिल हुए तथा छककर खाया-पिया। आगंतुकों के लिए उस बुढ़िया ने वीडियो पर फिल्में भी दिखलायीं। मानना पड़ेगा कि कुतिया ने भी क्या किस्मत पायी है?

111155

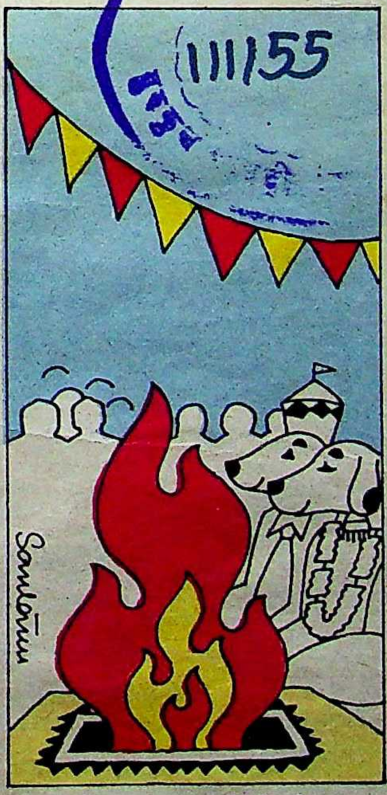

मरणोपरांत प्रोन्नति

अभी तक तो यही सुनने में आया था कि मरे हुए आदमी का नाम वोटर लिस्ट में है, तो जीवित का गुम है और मरे हुओं के नाम पर दूसरों की पौ बारह हो रही है। लेकिन सरकारी विभागों की तरह निजी संस्थानों ने भी ऐसी भांग खा रखी है कि उनके मुलाजिम भी कुछ-का-कुछ कर बैठते हैं। उप्र सरकार के शिक्षा विभाग ने तो पिछले दिनों अपने एक उच्च पदस्थ अधिकारी को दस साल पहले ही रिटायर घोषित कर दिया था। खैर, यह सब तो होता ही रहता है, लेकिन इधर हाल में जो घटित हुआ, वह तो और भी कमाल की बात है। हुआ यों कि बरेली स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवारत अध्यापक प्रवीन मोहन १९८७ में ही अपने प्रमोशन की लालसा लिए भगवान को प्यारे हो गये थे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जब ८८-८९ की प्रोन्नति सूची प्रकाशित की, तो उसमें उन्हें उपप्राचार्य के पद पर प्रोन्नत दिखा रखा था। काश! प्रवीन मोहन जिंदा होते और अपनी पदोन्नति का सुख भोग सकते।

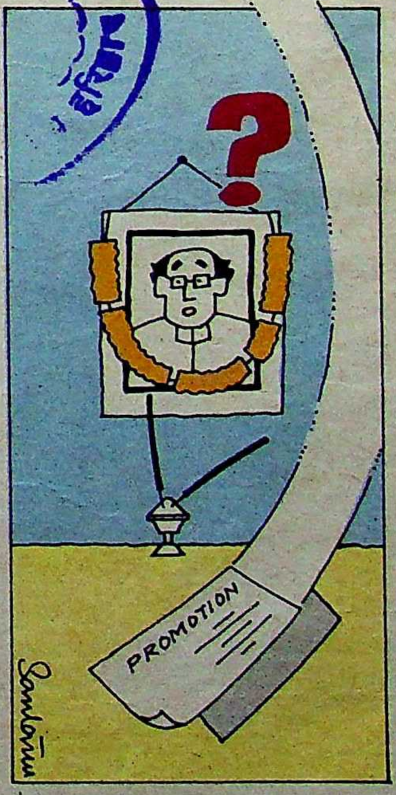

तस्कर बंदर

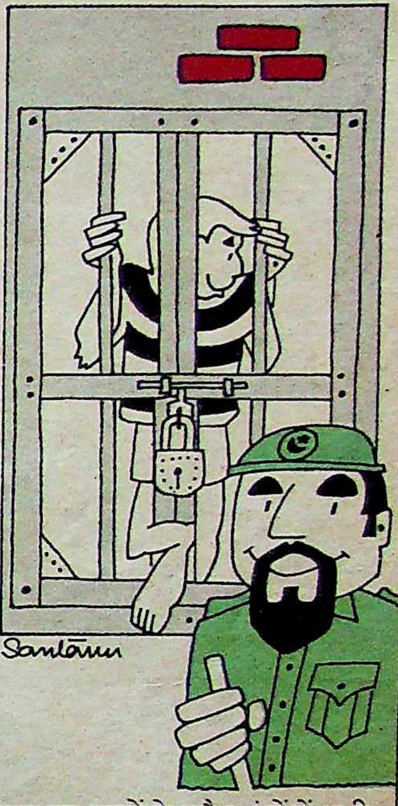

मादक द्रव्यों के अवैध धंधों में अभी तक तो खूबसूरत औरतों की भागेदारी की ही बातें सुनी जाती रही हैं, क्योंकि औरतों की वजह से कई दिक्कतें हल हो जाती हैं। वे माल को आसानी से यथेष्ट स्थान पर पहुंचाने में तो सफल होती ही हैं, साथ ही रोक-टोक करनेवालों से भी निपट लेती हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में एक बीजो नाम का बंदर गिरफ्तार किया गया है जो अपने मालिक मोहम्मद नईम के साथ इस धंधे में लगा हुआ था। बीजो इतना कुशल था कि ग्राहकों के पास मादक द्रव्य ले जाने और उनसे धन लाकर मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी। यदि कभी पकड़-धकड़ की नौबत आती, तो वह पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ जाता और फिर देखते-ही-देखते कहीं-का-कहीं पलायित हो जाता था। बलूचिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बीजो के पीछे पड़े थे, लेकिन बार-बार वह उनके हाथ से निकल जाता था। अंततः एक दिन उसे धर-दबोचा गया। लेकिन उसका मालिक फरार होने में सफल हो गया। अब नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड उस बंदर पर मुकदमा चलाने की सोच रहा है।

—संयोजन: डा॰ मुश्ताक अली

'मदर इंडिया' का गुस्सा

राखी ने 'राकी' में संजय दत्त की मां की भूमिका क्या निभायी कि फिल्म निर्माताओं ने उनके काले बालों में सफेदी पोत कर उन्हें नयी पीढ़ी के अभिनेताओं की 'मां' ही बना दिया। संजय दत्त ने तो बाकायदा अपनी इस प्रथम फिल्मी मां को 'मदर इंडिया' का ही खिताब दे दिया। वही मदर इंडिया उर्फ राखी आजकल धर्मेंद्र का नाम सुनते ही जल-भुनकर राख हो जाती हैं और धरम का नाम लेने वाले को सीधे 'गेट आउट' कर देती हैं। गर्म राख के भीतर छिपे राखी के अंगारे इसलिए दहकने लगे कि धर्मेंद्र ने एक फिल्म निर्माता की फिल्म में इसलिए काम करने से मना कर दिया क्योंकि वह अपनी फिल्म में धरम को राखी के बेटे की भूमिका देना चाहता था। धरम की आपत्ति थी कि फिल्म 'डकैत' में राखी ने मेरे बेटे सनी देवल की मां की भूमिका निभायी थी। अब सनी की मां भला कैसे मेरी मां बन सकती है।

धरम की बात सुनते ही राखी के तेवर बदल गये, "वह बुड्ढा अपने बेटे की माशूका (डिंपल) के साथ फिल्मों में रोमांस की पेंगें मार सकता है? श्रीदेवी के साथ दोनों बाप-बेटे हीरो की भूमिका निभा सकते हैं, तो शर्म नहीं आती और मेरा बेटा बनने में उसे नैतिकता याद आती है।..."

अब पता नहीं राखी की बात धरम तक पहुंची कि नहीं, लेकिन धरम की वही भूमिका अब जीतेंद्र निभा रहे हैं, जिन्होंने एक दर्जन फिल्मों में राखी के प्रेमी की भूमिका निभायी है।

तेरी मेहरबानियां

जब से श्रीदेवी ने रेखा की दोस्ती को ठेंगा दिखाया है, तब से रेखा ने उसे हर जगह मात देने की कसम खा ली है। जब उसे पता चला कि राकेश रोशन श्रीदेवी को लेकर फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके पास अपनी सारी पुरानी दोस्ती-दुश्मनी (अपने पूर्व मियां विनोद मेहरा की बदौलत) भूलकर पहुंच गयी। खुद-ब-खुद आयी रेखा को सामने देख हकबका-से गये राकेश रोशन ने श्रीदेवी वाली भूमिका रेखा को थमा कर निजात पायी। रेखा को लगा, मेहरबानियों की मात्रा अभी थोड़ी कम है, इसलिए राकेश के सिर से उतरे हुए विग को पुनः पहनाते हुए बोली, "तुम्हारी पिता के उम्र के लोग अभी भी बन-ठन कर हीरो का रोल कर रहे हैं और नये-नये अफेयर रचा रहे हैं। तुम्हारी तो उम्र अब हीरो बनने की हुई है!" और दुबारा फिर कैमरे के सामने न आने की खायी कसम को जेब में रखकर राकेश रोशन सचमुच रेखा के साथ कैमरे के सामने नमूदार हो गये।

रेखा की मेहरबानियों से आप्लावित, आउट हो गये एक दर्जन से भी अधिक निर्माताओं के 'बंद आफिस' अब गुलजार हो उठे हैं। रेखा की मेहरबानियों से आक्रांत श्रीदेवी ने जब सीधे हमला कर यश चोपड़ा की 'चांदनी' उनसे झटक ली, तो रेखा बोली, "उस गंजे (यश चोपड़ा) की चांद पर वह विग वाली (श्रीदेवी) भला क्या बिखेरेगी बुढ़ापे में चांदनी।"

रोमा मानिक छाया : तैयब बादशाह

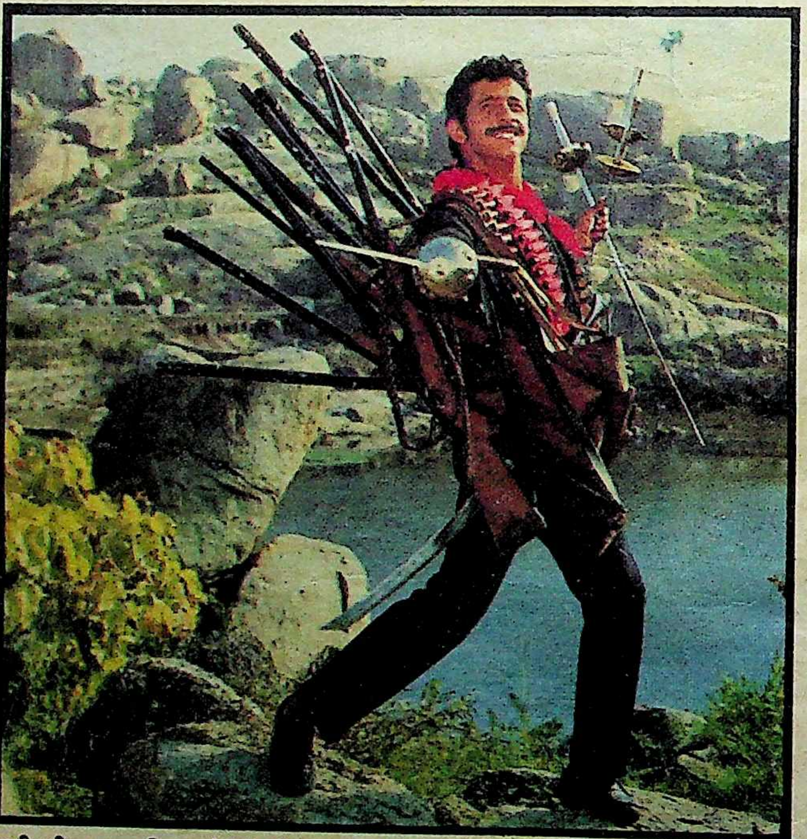

नसीरुद्दीन शाह फिल्म 'हीरो हीरालाल' में

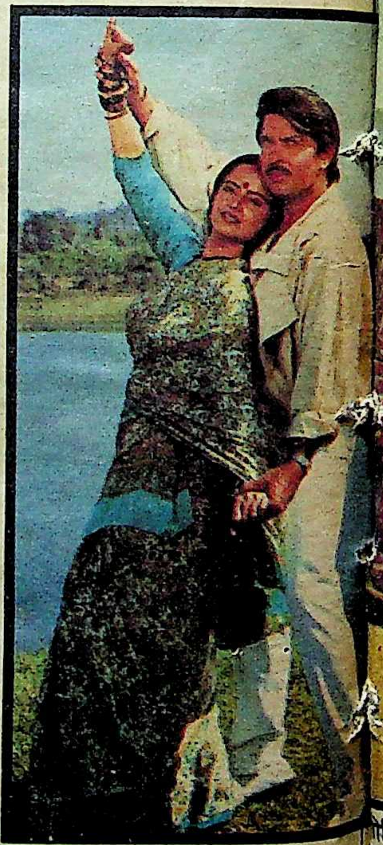

रेखा व राकेश रोशन

हीरो हीरालाल की फंतासी दुनिया

जब से नसीरुद्दीन शाह ने 'हीरो हीरालाल' में फंतासी हीरो की भूमिका निभायी है, तब से वह खुद फंतासी दुनिया में विचरण करने लगे हैं। फिल्म में वह ऐसे रिक्शा चालक की भूमिका में हैं, जो सपनों में फिल्म की नायिका को बचाने के लिए सैकड़ों खलनायकों को मिनटों में धूल चटा देता है।

वही हीरालाल अब अपनी निजी जिंदगी में भी फंतासी की दुनिया में कुछ इस तरह विचरण करने लगे हैं कि अब उन्हें अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना और गोविंदा तक की जमात तुच्छ लगने लगी है। सत्यजित राय की 'पथेर पांचाली' के बाद उन्हें सभी फिल्म या कला फिल्म निर्माता प्रतिभा-शून्य लगने लगे हैं। श्याम बेनेगल, जिन्होंने उन्हें अभिनय की दुनिया में प्रवेश और ऊंचाइयां दिलवायीं, से लेकर गोविंद निहलानी एवं बुद्धदेव दासगुप्त, जिनकी फिल्म 'पार' में उन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला, एकदम झख मारते-से नजर आते हैं।

सुभाष घई ने तो 'हीरो हीरालाल' से 'कर्मा' में ही कान पकड़ लिया। रमेश सिप्पी भी फंतासी लाल से कुछ इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म 'जमीन' से उन्हें निकाल कर ही फुर्सत की सांस ली। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी तो उनके नाम से भी कतराते हैं कि कहीं 'हीरो हीरालाल' की किरपा उन पर न हो जाये!

धरम-पति का धरम

एक ज्योतिषी ने गोविंदा को सलाह दी कि १९८८ में वह अ 'ह' अक्षरवाली फिल्म रिलीज क तो उसके सारे राहु-केतु व शनीचर ग्रह शांत हो जायेंगे। अपनी ७५ से अधिक फिल्मों की सूची पर नजर डालने पर उसे एक भी फिल्म 'ह'

तैयब बादशाह

ते हैं कि
किरण
दा को
ह अ
शनीव
७५ से
र नजर
ल्म 'ह'

छाया: तैयब बादशाह

ोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्रि

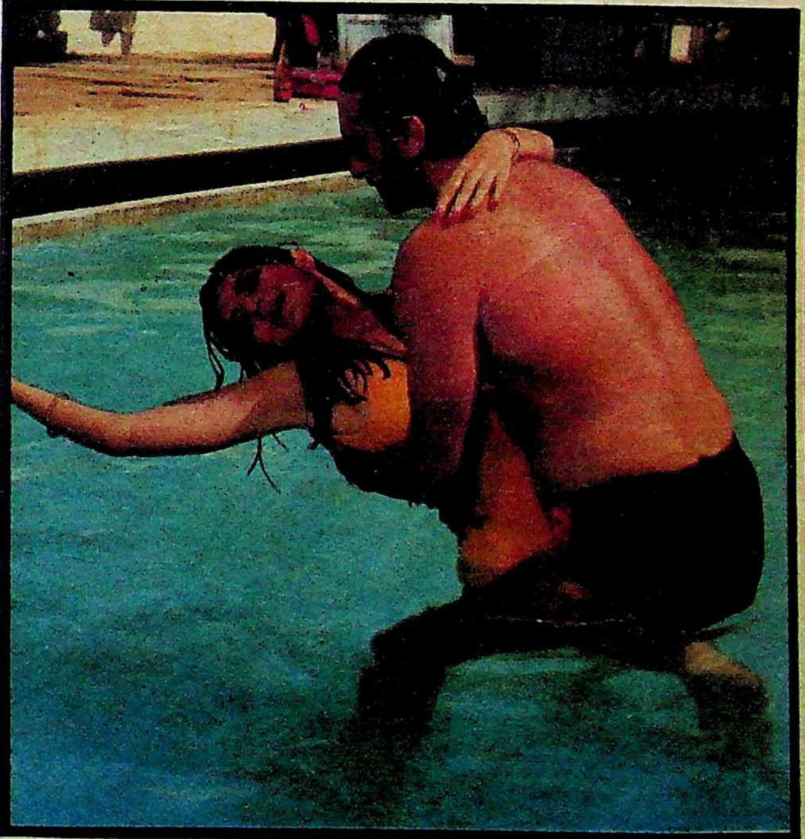

कबीर बेदी और सोनू वालिया

क्षरवाली नजर नहीं आयी, तो विदा ने निर्माताओं को दिये गये रीखों को स्थगित करके खुद अपनी ल्म 'हत्या' का निर्माण शुरू कर या।

गोविंदा सोच रहा था कि स निर्माता की हिम्मत है कि उस उंगली उठाये, लेकिन इन्हीं फिल्म त्राओं में एक थीं—हेमा लिनी जिनकी फिल्म 'आवारगी' लिए वह अनुबंधित थे। 'हत्या' नाने की जल्दी में गोविंदा भूल गये हेमा मालिनी का नाम भी 'ह' अक्षर से शुरू होता है। अब 'ही-मैन' कहे जानेवाले हेमा-पति धर्मेंद्र बीवी की रक्षा के लिए अपनी शूटिंग छोड़ आगे आ खड़े हुए। 'हत्या' के सेट पर पहुंचकर गोविंदा का कालर पकड़ा और लाकर 'आवारगी' के सेट पर खड़ा कर दिया। जब तक गोविंदा ने शूटिंग पूरी नहीं की, ही-मैन कुरसी डाले सेट पर पालथी मार कर बैठे रहे। अब ही-मैन के दिखलाये रास्ते पर दूसरे फिल्म निर्माता भी चलना शुरू कर दें, तो गोविंदा का क्या होगा?

संदो खान का नया कलमा

एक दशक पूर्व भूरी आंखों वाले 'वुमेन किलर' कबीर बेदी ने संदो खान बनने के लिए बंबई का मोह त्याग कर इटली, स्वीडेन और अंततः हालीवुड पहुंच कर लास एंजिल्स में डेरा जमा लिया, तो बंबई की फिल्मी पार्टियां बेरौनक हो उठी थीं। फिल्मी दुनिया में आचार्य रजनीश से भी बहुत पहले फ्री-सेक्स, नो लाइफ विदाउट सेक्स तथा प्लूटोनिक अफेयर का नारा बुलंद करने वाले बेदी दंपति आपस में तलाक लेकर अलग-अलग हाथ पीले कर लिये—प्रोतिमा ने हंसोड़ मसखरे आईएस जौहर से तथा कबीर ने ससून से निकाह पढ़ा लिया।

पूरे एक दशक के बाद संदो खान उर्फ कबीर बेदी को इहलाम हुआ कि जो बात बंबइया फिल्म इंडस्ट्री में है, वह भला हालीवुड में कहां? सो बोरिया-बिस्तर बांध कर वह बंबई आ पहुंचे।

राकेश ने अपनी फिल्म 'खून भरी मांग' में उन्हें रेखा के साथ नायक बना दिया। रेखा की सारी दिलकश अदाओं के बावजूद उन पर मुलम्मा चढ़ा सोनू वालिया के हुस्न का। वह भी कुछ इस कदर कि प्रोतिमा को अपनी दुनिया डगमगाती नजर आयी, जो कबीर को 'सुबह का भूला' मान दुबारा अपनी उजड़ी दुनिया आबाद करने के ख्वाब देख रही थी।

महाभारत की माद्री

जहा बड़ी-से-बड़ी अभिनेत्रियां बड़े निर्माताओं के साथ काम करने के लिए अपने ग्लैमर और सेक्स बम की इमेज पर भारतीय नारी की इमेज चस्पा करने की कोशिश में लगी रहती हैं, वहीं रोमा मानिक को अपनी भारतीय नारी की इमेज पर ग्लैमर और सेक्स का मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत आ पड़ी, क्योंकि बीआर चोपड़ा के सीरियल में न केवल उसे अल्प वस्त्र पहनना था, बल्कि 'राम तेरी गंगा मैली' मार्का झरना-स्नान का सीन भी देना था।

लेकिन असली मुसीबत तब आयी, जब बीआर चोपड़ा ने रोमा मानिक से पूछा, "तुमने महाभारत पढ़ा है? जानती हो माद्री कौन थी?

रोमा को पहले दो सवाल चीन की दीवार के समान लगे, अतएव उसने सीधे तीसरे सवाल को कैच कर लिया, "महाभारत बीआर चोपड़ा बना रहे हैं, मैंने उनका नाम सुना है।" बस चोपड़ा साहब को रोमा भा गयी और उसे समझाया, "माद्री पांडु की द्वितीय पत्नी थी। जब पांडु शिकार करते समय वन में विहार कर रहे कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी पर गलती से वाण चला बैठे, तो उन्होंने पांडु को शाप दिया, "जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, तो तुम्हारी मौत हो जायेगी।" अब माद्री की समस्या है कि अपने पति का कैसे स्पर्श करे...

रोमा उनकी बात काटती हुई बोली, "हाऊ सैड। तब तो कोई भी बेड रूम सीन नहीं होगा इस सीरियल में..."

—अखबारी लाल

साक्षात्कार/**कविता चौधरी**

'कल्याणी' मेरी प्रतिभा की जीवंत तस्वीर है

111155

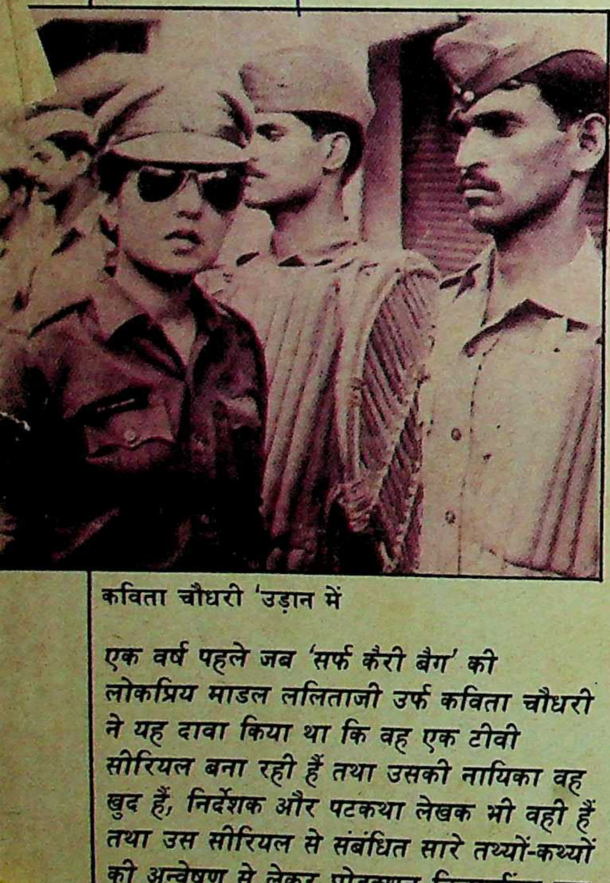

कविता चौधरी 'उड़ान में

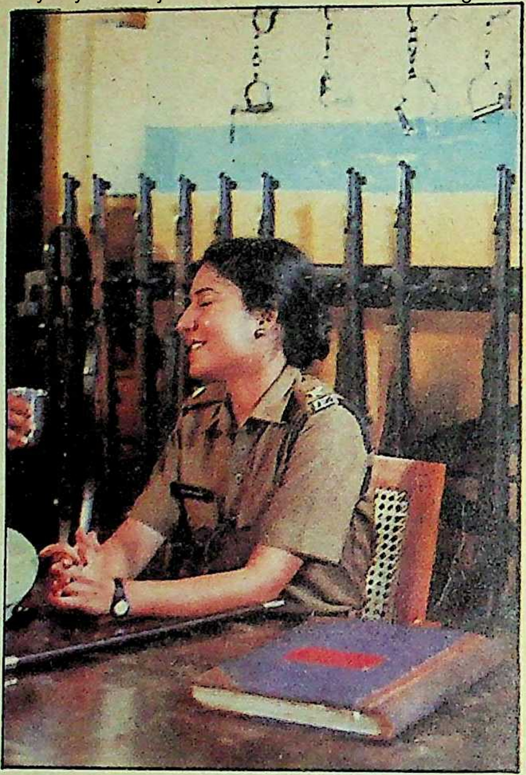

एक वर्ष पहले जब 'सर्फ कैरी बैग' की लोकप्रिय माडल ललिताजी उर्फ कविता चौधरी ने यह दावा किया था कि वह एक टीवी सीरियल बना रही हैं तथा उसकी नायिका वह खुद हैं, निर्देशक और पटकथा लेखक भी वही हैं तथा उस सीरियल से संबंधित सारे तथ्यों-कथ्यों की अन्वेषण से लेकर प्रोडक्शन डिजाइनिंग तक भी वही कर रही हैं, तो ताज्जुब हुआ था। और लगा था कि अपने कैरियर और धन पर आंख मूंद कर कुठाराघात कर रही हैं। लेकिन जब 'उड़ान' प्रदर्शित हुआ, तो यह भ्रम जाता रहा। 'उड़ान' ने न केवल लोकप्रियता हासिल की, बल्कि कविता चौधरी की प्रतिभा की सराहना भी हुई। कविता की विशेषता है कि वह किसी भी काम को पूरा करने तथा मनोवांछित परिणाम पाने तक पूरी तरह जुटी रहती हैं। ऐसा नहीं कि 'उड़ान' हर दृष्टि से बेहतरीन सीरियल है। कभी लगता है कि यह सिर्फ भारतीय पुलिस पर बनी मात्र एक डाक्यूमेंट्री है, तो कभी लगता है कि निर्देशक दर्शक के इमोशनल सेंटिमेंट को कैश करने के चक्कर में कामर्शियल फिल्मकारों के रास्ते पर भटक गयी है। बीच-बीच में 'जर्क' लगते हैं। लेकिन यह सारी बातें उस समय क्षम्य हो जाती हैं, जब पता चलता है कि यह उस कविता चौधरी का प्रथम प्रयास है जिसने सिर्फ नेशनल स्कूल आफ ड्रामा से डिप्लोमा लिया है, कुछ नाटक (अभिनय एवं निर्देशन) किये हैं तथा सीरियल बनाने के पहले तकनीकी ज्ञान के लिए शार्ट क्रशर कोर्स भर किया है। प्रस्तुत हैं, इस बारे में 'माया' से कविता चौधरी की बातचीत के अंश:

माया: ***'उड़ान' की कहानी इतनी प्रभावशाली क्यों है?***

कविता: दरअसल इसमें जीवन की सचाई है। अपने इर्द-गिर्द के प्रसंगों को चूंकि कहानी का रूप दिया गया है, इसलिए इसका असर है। यों जीवन की पीड़ा एवं सच्ची अनुभूति भी इसमें मुखरित हुई है।

माया: ***क्या एक साथ पटकथा, निर्देशन, अनुसंधान, एडिटिंग और अभिनय सभी के साथ आप न्याय कर पायी हैं?***

कविता: मैं इससे इनकार नहीं करती कि ये सारे काम एक साथ आसानी से किये जा सकते थे, फिर भी मेरे लिए तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहा कि इन सभी कामों को श्रेष्ठता तक पहुंचाऊं।

माया: ***आपनी सफलता में आपकी टीम का कितना योगदान रहा?***

कविता: 'उड़ान' की सफलता इस पूरी
योगदान के बिना न मिल पाती। विशेष
कैमरामैन बाबा आजमी (तन्वी किरण
और शबाना आजमी के भाई) इस यूनि
केवल कैमरामैन ही नहीं हैं, वह पूरी क
और उसके निर्माण के हर पहलू से पूरी
जुड़े हैं।

माया: ***क्या अब तक के प्रस्तुतीकरण से
संतुष्ट हैं? आलोचनाएं सुनकर कैसा लग
है?***

कविता: पूर्ण संतुष्ट कैसे होऊंगी? आप
की आलोचना ही तो भूल-सुधारने और
नया करने का मौका देती हैं। सीरियल
आरंभ के एपीसोड में कहीं-कहीं बैक ग्रा
म्यूजिक लचर पड़ा है। फेड-आउट (दृश्य
समापन) कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं हु

माया: ***कहानी के पूरे प्लाट को आप १३
में पूरा कर लेंगी?***

कविता: केवल १३ एपीसोडों में मैं उस
कहानी व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, जिस त
कल्याणी की कहानी बताना चाहती हूं।

माया: ***आप एक्सटेंशन क्यों नहीं मांगतीं***

कविता: मैंने अपनी ओर से 'एक्सटेंशन'
मांगा, लेकिन अगर काम अच्छा है, तो
एक्सटेंशन मिल भी सकता है, शायद अप
ही मिल जाये। बिना किसी सोर्स-सिफारि
अगर एक्सटेंशन मिला गया, तब मैं कल्य
किरदार के कई नये पहलुओं को दर्शक के
रख सकूंगी।

माया: ***ललिताजी से लेकर कल्याणी त
सफर कैसा रहा?***

कविता: ललिताजी का तो क्षेत्र ही अल
माडलिंग, जबकि कल्याणी मेरी पूरी प्र
जीवंत तस्वीर है।

माया: ***पुलिस प्रशिक्षण विशेषकर घुड़दौड़
सीखने के लिए आपने डुप्लीकेट का उपयो
किया था, लेकिन खुद कैसे घायल हो गय***

कविता: पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (हैदराब
में जब मैं इस दृश्य का रिहर्सल कर रही
तो लगा डुप्लीकेट काम तो बढ़िया कर र
लेकिन वह बात नहीं आ पा रही है, जो
चाहती हूं। मैंने खुद ही वह सीन करने क
निश्चय किया। कहानी के अनुसार मुझे द
घोड़े से जमीन पर गिरने का सीन देना थ
मेरा एक पैर रकाब में फंस गया और ब
जमीन पर गिरने के मैं दूर तक दौड़ते घो
साथ घिसटती हुई चली गयी। फलत: का
दिनों तक डाक्टरों एवं नर्सिंग होम की श
रहना पड़ा।

माया: ***'उड़ान' के बाद की उड़ान?***

कविता: कई विषय हैं दिमाग में, लेकिन
समय तो मैं 'उड़ान' के अलावा कुछ सोच
नहीं पा रही हूं।

—बंब

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित

Compiled
1999-2000

111155